1987
Aug-Dec

G [illegible] V.
Hardwar

111156

सर्वाधिक बिकनेवाली समाचार पत्रिका

माया

१५ अगस्त, १९८७ • मूल्य ४.०० रु०

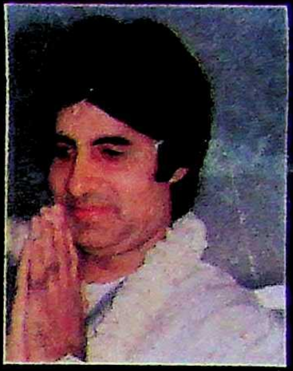

अमिताभ : इस्तीफा क्यों देना पड़ा ?

ेंकटरमण कैसे राष्ट्रपति सिद्ध होंगे ?

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर

दिल्ली : गगनचुंबी इमारतों में सुलगता खतरा

अजीत सिंह की राजनीतिक हैसियत

13

DUPLICATE

५|८|८७

11156

राजा की राजीव को खुली चुनौती

राजीव को ज्ञानीजी का आखिरी सबक

कर–राहत के लिए
कृपया ध्यान दें

6– वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों के

लाभ अनेक

6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (निर्गम-6 और निर्गम-7) में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के अन्तर्गत कर में छूट मिलती है।

निर्गम–6

- 1000 रु. 6 वर्षों में 1901 रु. हो जाते हैं।
- 11% ब्याज अर्द्ध वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। परिपक्व होने पर देय।
- आयकर छूट में लाभ क्योंकि ब्याज वार्षिक रूप से माना जाता है।

निर्गम–7

- 1000 रु. के निवेश से हर छमाही 55 रु. का लाभ और मूल राशि ज्यों की त्यों।
- 11% ब्याज अर्द्ध वार्षिक रूप से देय।
- नियमित आय योजना के रूप में एक आदर्श योजना।

दोनों ही निर्गम विभिन्न मूल्य वर्गों में उपलब्ध हैं। आपको जो अधिक उपयोगी लगे उसे चुनें।

कुछ विशेषताएं

- निवेश की कोई सीमा नहीं।
- नामजदगी की सुविधा उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम की धारा 80—एल के अन्तर्गत 7000 रु. तक ब्याज (दूसरी अन्य विनिर्दिष्ट ब्याज आय के साथ) आयकर से मुक्त है।
- अन्य विनिर्दिष्ट निवेशों सहित 5 लाख रु. तक निवेश सम्पत्ति कर से मुक्त है।
- प्रवासियों के निवेश पर 2% ब्याज अतिरिक्त मिलता है—यानि 13% प्रति वर्ष।

सभी
डाकघरों में
उपलब्ध

राष्ट्रीय बचत संगठन,
भारत सरकार

davp 87/183

मनोरमा

111156

१५ अगस्त '८७

स्त्री स्वास्थ्य

विशेषांक

रोग व स्वास्थ्य सम्बन्धी हर सवाल का जवाब जो आप डाक्टर से जानना चाहती हैं

प्रमुख आकर्षण

- ० हाय ये ज़ालिम मोटापा
- ० भाषा पहचानिए देह की
- ० महिलाओं में पीठ-कमर का दर्द
- ० सेक्स और स्वास्थ्य
- ० मेनोपॉज : जिंदगी रुकती नहीं
- ० डायटिंग : दस सिद्धान्त
- ० रक्तचाप : अपनी डाक्टर खुद न बनिए
- ० हारमोन और आपसे उनका वास्ता
- ० महिलाओं की एक आम समस्या : ल्यूकोरिया
- ० नाजुक बदन में लोहे का क्या काम ?
- ० वक्ष संबंधी आठ प्रश्न
- ० औरत की त्रासदी : पीरिएड पेन
- ० क्या आप आर०एच० निगेटिव हैं ?

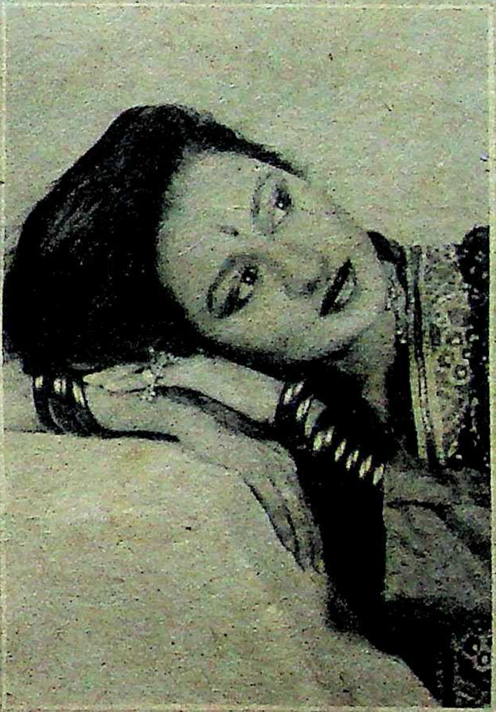

आवरण कथा :

औरत होने का दर्द :

बहुत से दर्द, तकलीफें और बीमारियां ऐसी हैं, जो महज औरत होने की वजह से आपको होती हैं। आम भारतीय औरतें न तो इन तकलीफों को ठीक ढंग से जानती हैं और न ही इनके उपचार की ओर ही कोई खास ध्यान देती हैं। फलतः उनका स्वास्थ्य खराब होता जाता है। जरूरी है कि हर महिला इन तकलीफों या बीमारियों को जाने और इनके प्रति जागरूक रहे। क्या हैं ये बीमारियां और इनसे कैसे बचा जा सकता है ?

अन्य आकर्षण

- ० कढ़ाई, एप्लीक और गृहसज्जा के कलात्मक नमूने
- ० तीज के अवसर पर : तीज तन से या मन से भी
- ० स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर : क्रान्तिकारी आन्दोलन और महिलाएं
- ० हरियाले मौसम का रंगारंग उपहार : भुट्टे और करौंदे के चटपटे व्यंजन
- ० पाकिस्तानी हास्य व्यंग्य : बोतल का जिन्न
- ० शफीकुर्रहमान की कहानी : लेडी डाक्टर

मूल्य-६.००

ग्लूकॉन-डी सुपरहीरो.

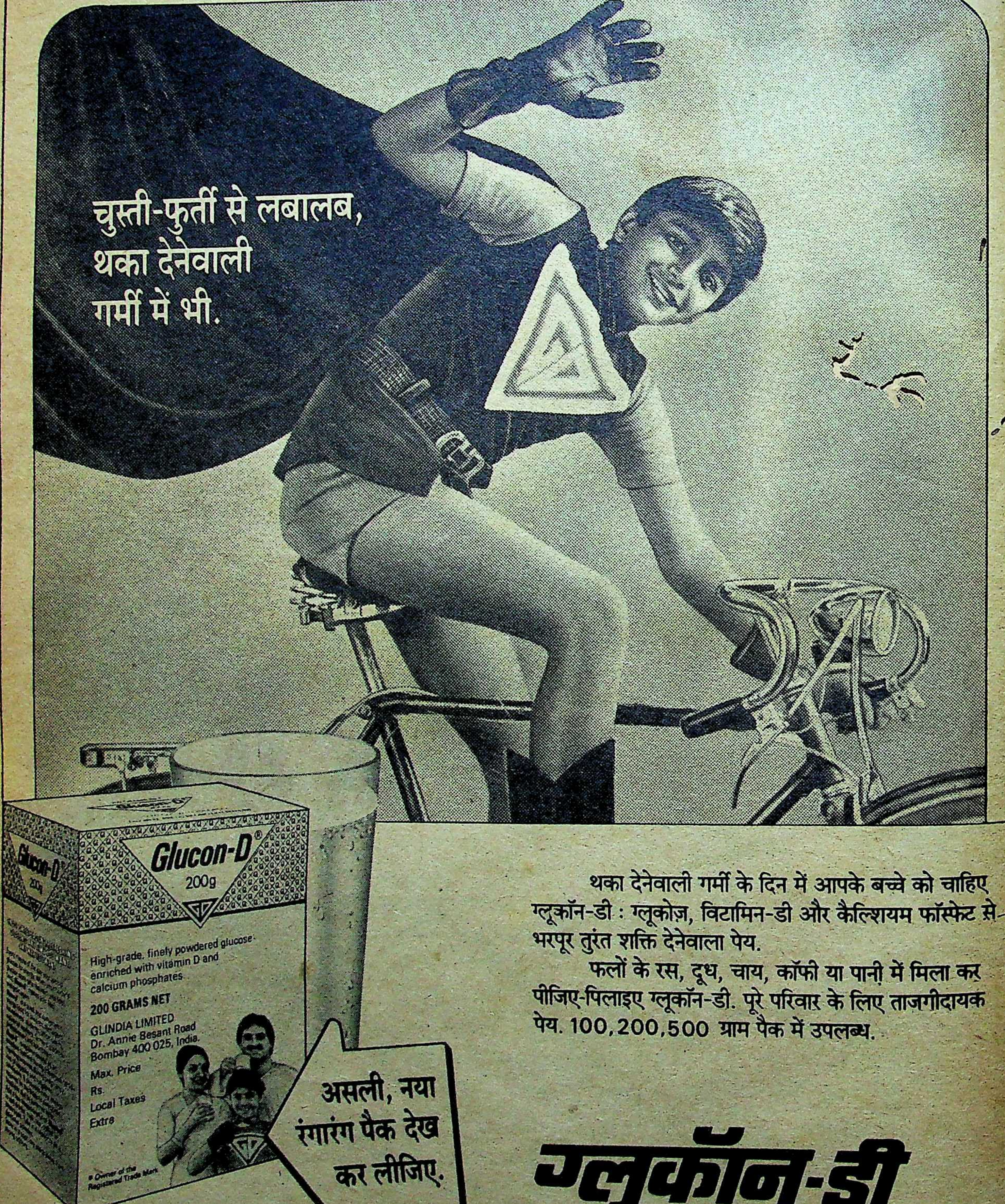
Glucon-D®
200g
High-grade, finely powdered glucose enriched with vitamin D and calcium phosphates
200 GRAMS NET
GLINDIA LIMITED
Dr. Annie Besant Road
Bombay 400 025, India.
Max. Price
Rs.
Local Taxes
Extra
® Owner of the Registered Trade Mark.

चुस्ती-फुर्ती से लबालब,
थका देनेवाली
गर्मी में भी.

असली, नया
रंगारंग पैक देख
कर लीजिए.

थका देनेवाली गर्मी के दिन में आपके बच्चे को चाहिए ग्लूकॉन-डी : ग्लूकोज़, विटामिन-डी और कैल्शियम फॉस्फेट से भरपूर तुरंत शक्ति देनेवाला पेय.

फलों के रस, दूध, चाय, कॉफी या पानी में मिला कर पीजिए-पिलाइए ग्लूकॉन-डी. पूरे परिवार के लिए ताजगीदायक पेय. 100,200,500 ग्राम पैक में उपलब्ध.

ग्लूकॉन-डी

शक्ति देनेवाला पेय... सुपरहीरो की खास पसंद.

HTA 1097

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक १५

माया

१५, अगस्त १९८७

यह अंक

माया
राजा की राजीव को खुली चुनौती

आवरण कथा

१६ अरुण नेहरू, आरिफ और फिर वी०पी० सिंह के कांग्रेस से अलग होने के कारण राजीव गांधी का सिंहासन डगमगाने लगा है। इस्तीफों और निष्कासन का निरंतर क्रम जारी है। राजा और राजीव का यह घमासान युद्ध क्या करवट लेगा?

अमिताभ

अमिताभ जैसे जिगरी दोस्त से आखिर राजीव गांधी को पीछा क्यों छुड़ाना पड़ा? अजिताभ का मकान-प्रकरण क्या मोड़ ले सकता है? २५

वेंकटरमण

विषम समय में निर्वाचित राष्ट्रपति वेंकटरमण संविधान के रक्षक सिद्ध होंगे या प्रधानमंत्री के इशारों पर चलनेवाले?
३५

मध्य प्रदेश

मंत्री सिद्दीकी और विधायक सिद्दीकी के बीच जंग क्यों छिड़ी हुई है? मोतीलाल वोरा का भविष्य अधर में क्यों है?
५०

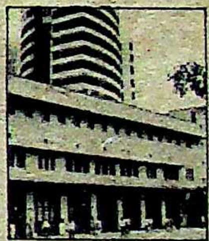

दिल्ली

राजधानी की ८० लाख की आबादी की रक्षा के लिए ६३ दमकल केंद्र चाहिए लेकिन हैं सिर्फ १३। दिल्ली को आग से कौन बचायेगा? ५७

उत्तर प्रदेश

नकवी, सिंह, शास्त्री आदि मंत्रियों के निकलने के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ शुरू हुई बगावत क्या सफल हो पायेगी?
४०

बिहार

सभ्यता और संस्कृति के लिए विख्यात मिथिलांचल का वैभव आज क्यों लुटा हुआ है? एक सर्वेक्षण रिपोर्ट:
४४

दिल्ली दरबार: हमने देखा, मगर क्या? ६
प्रसंगवश: अजीत सिंह की राजनीतिक हैसियत २९
प्रसंगवश: अजीत सिंह का साक्षात्कार ३२
मध्य प्रदेश: मोतीलाल वोरा पर खतरे की घंटी ४९
राजस्थान: नाथद्वारा में जातीय उपद्रव ५२
विवाद: पंजाब में मुख्यपंथी क्या कर रहे हैं? ६२
घटनाक्रम: ऋषिकेश: आतंकवादी तो यही चाहते थे? ६४
सुरक्षा: सैन्य गुप्तचरी का जाल ६६
राडार: प्रधान मंत्री की सुरक्षा के नाम पर ६९
व्यक्तित्व: अमजद अली खां: सरोद और जिंदगी की जुगलबंदी का दूसरा नाम ७२
व्यक्तित्व: अमजद अली खां से बातचीत ७४
फोटोफीचर ७७
कला: स्वादिष्ट कला ८१
फिल्म: इप्टा के पचास वर्ष: लेकिन 'राम अवतार एम०एल०ए०' हार गया ८३
लोग ८८

इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

आवरण पारदर्शी: अमरेंद्र दुबे (वी०पी० सिंह)

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
विशेष संवाददाता
दिल्ली: राहुल देव
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
दिल्ली: पुनीत टंडन
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक:
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा:
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

"Air Surcharge 50 Paise Per copy" Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Imfal, Tejpur, Shillong, Dimapur & Kathmandu and 25 Paise Agartala

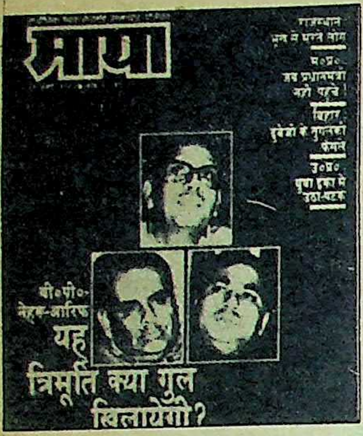

दोस्ती किधर ले जायेगी... ?

‘राजीव- अमिताभ : क्या दोस्ती ले डूबेगी ?’ तथ्यपरक जानकारी के लिए हार्दिक बधाई। आपकी शत-प्रतिशत भविष्यवाणियां सही निकली हैं और इसमें भी शक नहीं कि समय रहते प्रधानमंत्री ने सही व्यक्तियों को नहीं परखा और विश्वास में नहीं लिया, तो वह दिन दूर नहीं जब राजीव सरकार सत्ताच्युत हो जायेगी। —नजीर मुहम्मद खान, काशीराम राजपूत, रानीपुर, उ०प्र०

राजीव-अमिताभ : ‘क्या दोस्ती ले डूबेगी’ पढ़ा, इससे स्पष्ट होता है कि राजीव को अपनी दोस्ती केवल पारिवारिक मामले तक ही रखनी चाहिए न कि राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में सभी के साथ सद्व्यवहार व निष्पक्षता रखनी चाहिए। इससे पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः राजीव को अमिताभ के साथ पारिवारिक संबंध ही रखना चाहिए, जिससे उनकी छवि धूमिल न हो। —ब्रह्मानंद शर्मा, नंगसा सूरौठ, राज०

माया’ (१५ जुलाई) में राजीव-अमिताभ-दोस्ती पर लेख पढ़ा। वर्तमान परिस्थिति में विवादों से घिरे दोनों दोस्त क्या दोस्ती को पूर्ववत् रख पायेंगे ? अमिताभ भले ही सफल अभिनेता हों, पर राजनीति में उन्हें असफलता ही प्राप्त हुई है। उनके कारण राजीव की परेशानियां बढ़ी ही हैं। आगे से अच्छा होगा कि अभिनेता अभिनय तक ही सीमित रहें, सक्रिय राजनीति उन लोगों के बस की बात नहीं।—जयकांत, वैशाली, बिहार

कुत्ता बनाम चोर

मैंने ‘माया’ का जुलाई, ’८७ अंक पढ़ा। राजीव गांधी द्वारा यह कहे जाने पर कि ‘मैं हर भोंकने वाले कुत्ते का जवाब नहीं देता’ एक प्रधानमंत्री की हैसियत से ठीक नहीं तथा जेठमलानी द्वारा प्रत्युत्तर में यह कहना कि ‘कुत्ता चोर को ही देखकर भौंकता है’ भी अनुपयुक्त है। जेठमलानी भले ही उम्र में हमारे प्रधानमंत्री से बड़े हों, किंतु उनका देश के प्रधानमंत्री से ऐसे कहना उचित नहीं। दोनों के बीच चल रहे इस प्रश्नोत्तर से देश की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा करके वे विदेशियों को भारत के ऊपर हंसने का मौका दे रहे हैं।—अजय कुमार खंडेलवाल, ६ पल्टन बाजार, प्रतापगढ़, उ०प्र०

वीर बहादुर का खेल

माया’ के (१५ जुलाई) के अंक में प्रसंगवश के अन्तर्गत ‘वीर बहादुर सिंह का खेल’ पढ़ा। वाकई वीर बहादुर सिंह ने दिल्ली दरबार को रिझाने के उद्देश्य से विश्वनाथ प्रताप सिंह की गोरखपुर की पूर्व निर्धारित सभा को सांप्रदायिक रंग देकर विघ्न डाला। दिल्ली दरबार को खुश करने की इस हरकत व वी०पी० सिंह की गिरफ्तारी से स्वयं कांग्रेस-इ को नुकसान पहुंचा है। आम जनता में वी० पी० सिंह की छवि पाक-साफ नेता के रूप में तेजी से उभर चुकी है। उसे किसी हालत में किसी विधि से भी धूमिल करना लगभग असंभव है। फेयरफैक्स, बोफोर्स व जर्मनी के पनडुब्बी वाले कांड से जनता का विश्वास, सरकार के ऊपर से उठने लगा है। लोगों का ध्यान अब सरकार के बजाय वी०पी० सिंह पर जाने लगा है। ऐसे में केंद्र व प्रदेश सरकार उनकी सभाओं को न होने देकर जनता का गुस्सा अपने ऊपर ओढ़ने का खतरनाक खेल खेल रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो आगे भी नुकसान कांग्रेस-इ का ही होगा।—आर०आर० ओझा, सफदरभारी, फैजाबाद, (उ०प्र०)

‘माया’ १५ जुलाई, ’८७ ‘वीर बहादुर सिंह का खेल’ आद्यंत पढ़ा जिसमें १५ जून को गोरखपुर में राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सभा को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यूह रचना की थी। जिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भंग करके राजा साहब की सभा को रोकने का असफल प्रयास किया गया और उन्हें ‘गिरफ्तार’ किया गया उससे कांग्रेस-इ की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा है और सरकार की कथनी और करनी की भिन्नता स्पष्ट हुई है। इस प्रकार की अलोकतांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर सरकार अपनी छवि धूमिल कर रही है। —त्रिलोकीनाथ यादव, प्रधानाचार्य, लाल बहादुर शास्त्री उ०मा०वि०, मुसहा, बस्ती

हरिजन होना पाप है ?

‘माया’ (जुलाई, प्रथम पक्ष) का एक लेख ‘हरिजनों की दुर्दशा से बेखबर’ पढ़ा। यह शोचनीय एवं गंभीर बात है कि आजादी के चालीस वर्ष बाद भी हरिजनों का आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक शोषण हो रहा है।... राजनेता भी इनका शोषण कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकते हैं। विगत जून में ‘हरिजन सेवक संघ’ की ओर से सुप्रसिद्ध नाथद्वारा मंदिर में ‘हरिजन प्रवेश’ का वृहत् कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन नाथद्वारा के पंडों व अंध श्रद्धालुओं को सरकार का यह ढोंग पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया और बंद का भी आयोजन किया। अंततोगत्वा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, फिर भी उपद्रव हो ही गया। आजादी के चालीस वर्षों बाद भी ‘हरिजन मंदिर प्रवेश’ का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। ‘हरिजन’ हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, उनका शोषण तो बंद होना ही चाहिए। —श्याम मनोहर व्यास, उदयपुर, राजस्थान

समझदार लोग और उनकी समझ

१५ जुलाई, ’८७ के ‘माया’ में जैनमुनि सुशील कुमार एवं प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी की भेंटवार्ता पढ़कर यही लगा कि शांति की वकालत करने वाले ये दोनों सज्जन संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। काश ! ये समझ पाते कि हिंदू और सिख अलग नहीं हैं।

प्रधानमंत्री अपनी गलतियों को सुधारें...

‘माया’ १५ जुलाई, ’८७ में आवरण कथा—‘राजीव-अमिताभ : क्या दोस्ती ले डूबेगी ?’ पढ़कर मन विक्षिप्त हुआ। यदि प्रधानमंत्री की पारिवारिक मित्रता बच्चन परिवार से है, तो यह व्यक्तिगत मामला है। इसे समष्टिगत बनाकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आंकना कहां तक उचित है ? संबंधों की प्रगाढ़ता को लेकर छीछालेदर करने में टंडनजी ने बहुत ही तत्परता दिखायी। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद। निस्संदेह फेयरफैक्स व रक्षा सौदों में दलाली ने प्रधानमंत्री व कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता को धूल चटा दी है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब मामला भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ (पूर्व) मंत्री व देश के प्रति समर्पित सिपाही वी०पी० सिंह के कर कमलों द्वारा प्रकाश में आया। आज राजीव गांधी की असफलता का जो भी गुणगान पत्रिकाओं एवं विपक्षियों के माध्यम से हो रहा है, सब वी०पी० सिंह के इस्तीफे व उससे उपजे राजनीतिक समीकरण का परिणाम है। जहां तक हरियाणा चुनावों का सवाल है, कांग्रेस की नाव भ्रष्टाचार एवं रक्षा सौदों में दलाली के कारण ही डूबी। जार्ज साहब की धौंस जनता में सिर्फ कांग्रेस के प्रति शंका पैदा करने की साजिश है। १९७७ के आम चुनाव में विपक्षी दिग्गजों की कारगुजारी से पूरा देश वाकिफ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रतिष्ठित नेता कोई रचनात्मक कार्य न कर बस कीचड़ उछालने में संलग्न होकर देश को कौन-सा नया आयाम प्रदान करेंगे ? अतः पार्टी या दोस्ती किसी को भी अलविदा कहना कतिपय उचित नहीं। जहां तक राजीव गांधी की गलतियों का सवाल है, इसकी व्याख्या ‘इंसान से गलतियों’ के संदर्भ में होनी चाहिए। यह तो कटु सत्य है कि यदि प्रधानमंत्री अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो राजनीति से काल-कवलित हो जायेंगे—राजीव कुमार शर्मा, ग्रा०—महादेवपुर, पो०—बनमनखी, जि०—पूर्णियां, बिहार

चिट्ठियां

हिंदू और सिख को अलग मानकर सांप्रदायिक सद्भाव की बात करना उचित न होगा। सिख समाज को पूरे हिंदुस्तान को अपना समझकर खोये विश्वास को पुनः प्राप्त करना चाहिए। हिंदू-सिख अलग नहीं हैं, यह समझना चाहिए।—राजीव कुमार ओझा, पत्रकार, नाथ सदन, चुनार, मिर्जापुर, उ०प्र०

'माया' १५ जुलाई, '८७ पढ़ी। क्षत्रिय महिला सम्मेलन एवं 'माया' से बीनू जोधा का साक्षात्कार काफी रोचक लगा। लेकिन, केवल सम्मेलन करने से ही राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा नारी शोषण, बाल-विवाह, बालिका-वध, परदा-प्रथा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि एक जनांदोलन छेड़ा जाये, ताकि सारे समाज का सोच बदल सके। आज के इस बदलते परिवेश में पुरुषों को दमनात्मक रवैये का परित्याग करना होगा, अन्यथा हम और पिछड़ते चले जायेंगे। क्योंकि परिवार रूपी गाड़ी सिर्फ पुरुष रूपी पहिये पर कदापि नहीं चल सकती। —ठाकुर सुरेश सिंह, मानपुर (दिधवारा), जिला सारण

अमृता

'माया' १५ जुलाई, १९८७ पढ़ी। 'अमृता : अपने ढंग का पहला सीरियल' पर लेखक हरीश तिवारी की टिप्पणी पढ़कर बहुत अच्छा लगा। 'अमृता' वास्तव में एक स्मरणीय सीरियल है। इस सीरियल में अमर कवियों की अमर कविताओं को बहुत अच्छे ढंग से संजोकर प्रस्तुत किया गया है। अजीत सेठ ने 'अमृता' का निर्माण कर हिंदी के लोकप्रिय कवियों को देश के उन कोनों तक पहुंचाया है, जहां के निवासी हिंदी नहीं जानते हैं। सबसे ज्यादा योगदान तो अमर संगीतकार स्व० जयदेव का है, जिन्होंने अमर कवियों की कविताओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से खुद की विशिष्ट शैली में, जो अति प्रशंसनीय है, संगीतबद्ध किया है। जिस प्रकार हिंदी भाषा के कवियों ने तन-मन-धन से इन कविताओं की रचना की है, मानो 'अमृता' सीरियल का निर्माण कर इनमें जान फूंक दी हो। ये कविताएं श्रोताओं के मन पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है—इसका भी सफलतापूर्वक कविता के साथ-साथ फिल्मांकन किया गया है। इस प्रकार के फिल्मांकन से हिंदी भाषा नहीं समझनेवाला भी, कविता का अर्थ समझ जाता है।—रवींद्र शुक्ला, सुरेला (रंधीर), जि०—होशंगाबाद, म०प्र०

ज्योति बसु का राजीव प्रेम

'माया' (३० जून) की सूक्ष्म दृष्टि ने यह रहस्य आखिरकार उजागर कर ही दिया कि जो ज्योति बसु कुछ समय पूर्व तक राजीव गांधी के प्रति विष वमन किया करते थे, वे आज उनके समर्थक हो रहे हैं। ज्योति बसु का यह कहना कि 'राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं', इस बात का संकेत है कि राजीव सरकार का पतन उनका स्वयं का पतन है। लोकप्रियता की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी तथा लोकदल जैसी दक्षिणपंथी पार्टियां ही सत्ता में आयेंगी जो किसी भी कीमत पर सी०पी०एम० को पनपने नहीं देंगी, लेकिन इसके विपरीत सोवियत संघ के विश्वसनीय मित्र के रूप में राजीव गांधी कम्युनिस्ट सरकारों को अपदस्थ नहीं करेंगे।—रामसेवक गुप्ता, १४२, आदर्शनगर, फीरोजाबाद, आगरा, उ०प्र०

जनता को मूर्ख समझना स्वयं को...समझना है !

'माया' के ३० जून के अंक में डा० पुष्पेश पंत के अभिमत से सभी सहमत होंगे कि भयंकर बहुमत ने सरकार की अहंकारी, निरंकुश प्रवृत्ति को अनिवार्यतः बढ़ावा दिया है। स्थिति यह हो गयी है कि बिना देश-द्रोही बने असहमति व आक्रोश व्यक्त करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। इसे संभव कर दिखाया है, आरिफ मोहम्मद खां ने अपने दिये हुए साक्षात्कार में, अपने मत को साहस के साथ व्यक्त कर।...वैसे भी जनता को मूढ़ समझनेवालों को इसका जवाब पहले भी मिल चुका है और आज हरियाणा की जनता ने जो धोबीपाट लगाया है वह समस्त भारतीय जन-मानस का आक्रोश ही है। वह जानती है कि असली जयचंद व मीरजाफर कौन हैं? —डा० मदन मोहन सिंह, भवानी होमियो हाल, जौनपुर, उ०प्र०

खयालात

जब तक प्रधानमंत्री को संसद का बहुमत प्राप्त है, तब तक दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस पद से नहीं हटा सकती।

—राष्ट्रपति आर० वेंकटरमण

उगते सूरज से अस्त होते सूरज की आभा ज्यादा तेज होती है।

—निवर्तमान राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह

हम अपने नेता से सांप्रदायिक तत्वों और आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो हमारे ही खिलाफ कार्यवाही कर दी।

—आरिफ मोहम्मद खां अपने कांग्रेस-निष्कासन पर

राजीव गांधी से तो कल्पनाथ राय ज्यादा अच्छा है।

—निष्कासन के बाद विद्याचरण शुक्ल

मैं विश्वास, प्यार और स्नेह देनेवाली इलाहाबाद की जनता की व्यक्तिगत रूप से सेवा करता रहूंगा। मैं जो भी कार्य करूंगा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में करूंगा।

—संसद से त्यागपत्र देने के बाद अमिताभ बच्चन

गोडसे को भी तत्काल फांसी नहीं दी गयी थी, लेकिन क्या अब कांग्रेसी स्पष्टीकरण का मौका पाये बिना अखबारों के जरिये राजनीतिक मृत्यु-दण्ड प्राप्त करेंगे?

—वी०पी० सिंह, अरुण-आरिफ-शुक्ल के निष्कासन पर

यह कांग्रेस पार्टी के टूटने की शुरुआत है।

—भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी

पड़ोसी के घर में आग तेज है, देखें क्या होता है?

—लोकदल-ब अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा

कांग्रेस-इ अध्यक्ष का यह कदम (निष्कासन) दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोशिश यह है कि इससे कांग्रेस के सांसद और विधायक विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना बंद कर देंगे, तो यह कोशिश सफल नहीं होगी।

—निष्कासन के बाद अरुण नेहरू

मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत के लोग भ्रष्ट कांग्रेस-इ सरकार को अभी भी क्यों बरदाश्त किये हुए हैं।

—आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन०टी० रामाराव

हरियाणा में लोकदल का कोई आधार नहीं है, यह देवीलाल सरकार छह महीने में गिर जायेगी।

—भजनलाल

विद्याचरण शुक्ल ५० साल से कांग्रेस में थे। उनके पिता जिंदगी भर कांग्रेसी रहे। उन्हें ऐसे लोगों ने निकाल दिया जिन्हें पार्टी में शामिल हुए दो-तीन साल हुए हैं। **—पं० कमलापति त्रिपाठी**

आरिफ

अमिताभ बच्चन

पं० कमलापति

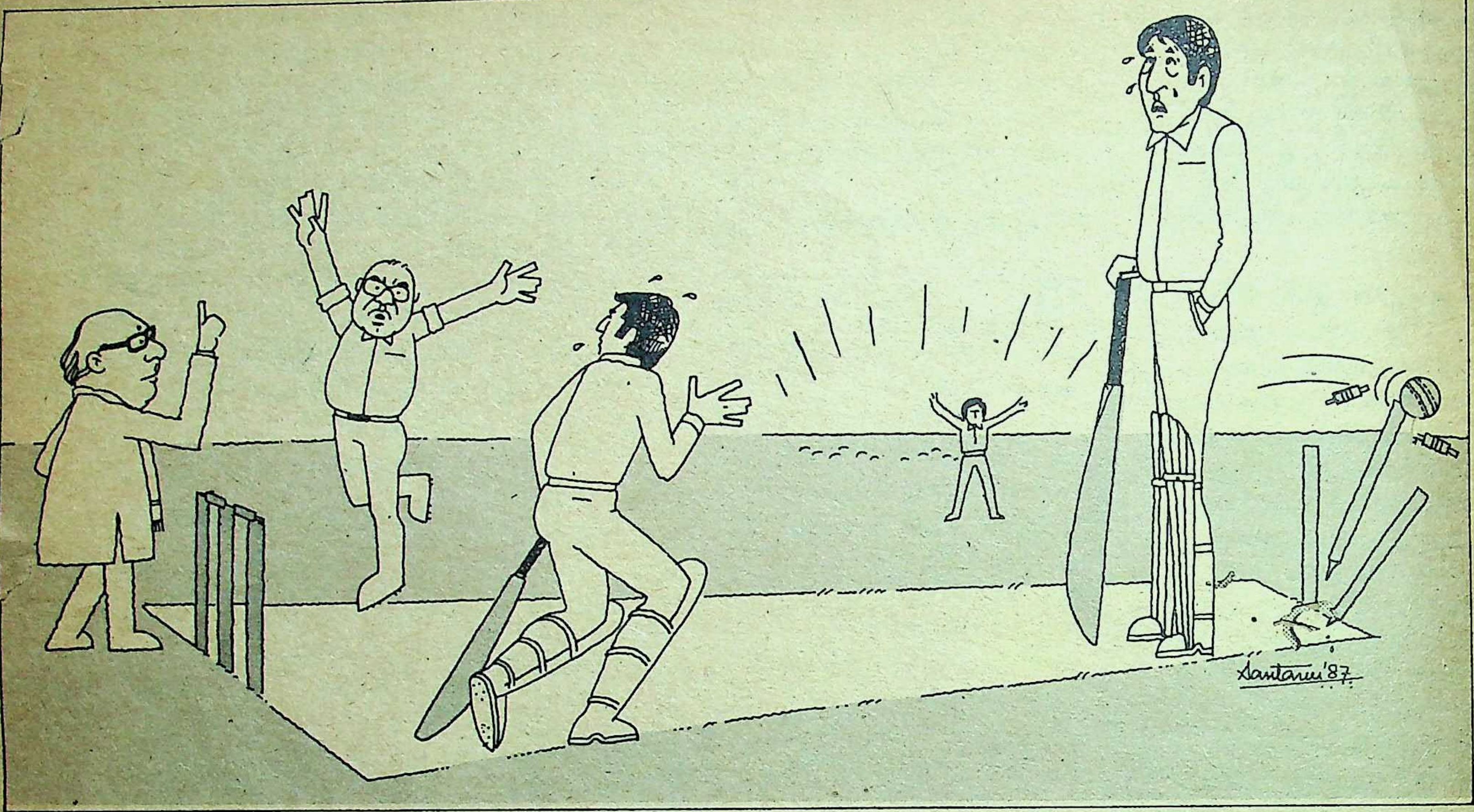

हमने देखा, मगर क्या ?

इस महान देश के वासियों को इस समय एक अभाव बड़ी बुरी तरह से कचोट रहा है। देश की राजनीति इस समय क्रिकेट के एक दिवसीय मैच की तरह रोमांचक क्षणों में पहुंच चुकी है, लेकिन रनिंग कमेंट्री का कोई इंतजाम नहीं। यदि ऐसा होता तो सुनने को मिलता: रेसकोर्स के बोफोर्स स्टेडियम से मैं फलनवा बोल रहा हूं। जैसा कि हमने देखा, दिल्ली में मानसून ने न पहुंचकर पिछले ८० साल का रिकार्ड ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इटली में बाढ़ आयी हुई है, इसलिए पिच में थोड़ी नमी है। बुलडोजर टीम के कप्तान राजा मांडा ने भारी रोलर की मांग की। धीरे-धीरे रोलर घुमाया जा रहा है। हमने देखा 'टास' राजा मांडा ने जीता है और उन्होंने आल फ्रेंड्स टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। अब हमें देखना है कि आल फ्रेंड्स टीम के कप्तान मि० क्लीन सलामी बल्लेबाज के रूप में किसको उतारते हैं। जैसा कि उम्मीद थी ओपनिंग के लिए अमिताभ-अजिताभ की देश से ज्यादा विदेशों में प्रसिद्ध जोड़ी को उतारा गया है। जैसा कि आप जानते हैं अजिताभ हाल में ही स्विट्जरलैंड में कबड्डी खेल कर लौटे हैं और अमिताभ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने सफलता की हर रेखा को पार किया है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी राजा मांडा ने खुद संभाली है। वह डिफेंस एंड से अटेक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि खेल के आगे का हाल सुनाया जाये, कल्पनाथ राय से राजा मांडा की गेंदबाजी के बारे में एक्सपर्ट कमेंट सुनिए। कल्पनाथ राय मुंह से बोलना शुरू करते हैं:"राजा मांडा को मैं सात पीढ़ियों से जानता हूं। वह एक मक्कार गेंदबाज हैं। क्रिकेट की गेंद चुरा-चुरा कर वह गेंदबाज बने हैं। वह बाउंसर फेंकते हैं और एक बार हमारे कप्तानजी, जिनके बराबर ब्रह्माण्ड में कोई नहीं, के सीधे चेहरे पर गेंद मारी थी।" कमेंटेटर बीच में ही बड़ी मुश्किल से कल्पनाथ राय से माइक छीन कर बोलना शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि राजा मांडा अब धीरे-धीरे अपने बालिंग ग्राउंड पर बढ़ रहे हैं। अब वह मुड़े और तेज दौड़ना शुरू किया। गेंद ने अमिताभ के बल्ले का बाहरी कोना चाटा, वह भाग्यशाली रहे, नहीं तो विकेट कीपर भूरे लाल उनको कैच आउट कर सकते थे।

गेंद को जेठमलानी ने कलेक्ट किया और राजा को दिया। राजा अपने मार्ग पर आगे बढ़े, पीछे मुड़े, दौड़े, अंपायर पं० कमलापति त्रिपाठी को पार किया और...यह अमिताभ आउट...बिना खाता खोले। राजा ने यह गुगली फेंकी थी जो अमिताभ को समझ में नहीं आयी और वह अपना विकेट गंवा बैठे। एक्सपर्ट कमेंट्स—हेमवती नंदन बहुगुणा। बहुगुणाजी कमेंटेटर पर लोकदलीय शैली में गुस्सा होते हुए बोले: "देखिए आप गलत बोल रहे हैं, अमिताभ ने खाता खोला है।" कमेंटेटर हंसकर कहते हैं: "बहुगुणाजी खेल से राजनीति को दूर रखिए।" "अच्छा-अच्छा, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह हीरो नहीं, जीरो है और जीरो ही रहेगा।" बहुगुणाजी के कमेंट्स के बाद विशेष दीर्घा में बैठे राजबब्बर और रेखा ने जोर-जोर से तालियां पीटीं। अमिताभ वापस पैवेलियन में...

काश, रनिंग कमेंट्री हो या न हो, लेकिन इस समय हर पल जो पट परिवर्तन हो रहा है, रोजाना जो विकेट गिर रहे हैं, वह नजारा कम रोमांचक नहीं है।

राजा मांडा के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर ने रोकने का दुस्साहस किया है, इसलिए पानीपत की पहली लड़ाई यहीं होगी। ११ जुलाई को राजा लखनऊ में ही थे। राष्ट्रपति के चुनाव के पहले राजा की लखनऊ में उपस्थिति से दिल्ली दरबार की कंपकंपी छूटना स्वाभाविक थी। फौरन अर्जुन सिंह, नवल किशोर शर्मा, सीताराम केसरी और एच०के०एल० भगत को दौड़ाया। उस दिन जब वह पार्टी में एकता बनाये रखने का प्रवचन दे रहे थे, तो असंतुष्ट खुले आम बगावत के झांझ-मंजीरे बजा रहे थे। कल तक जिन मंत्रियों-

विधायकों को वह घास नहीं डाल रहे थे, अब पीठ पर हाथ फेर-फेरकर जलेबी खिलाने में लगे थे। वीर बहादुर सिंह विधायक असलम शेर खां से बड़ी विनम्रता से कह रहे थे। कहो असलम मिलते नहीं हो, क्या कर रहे हो। "बस पार्टी को मजबूत कर रहा हूं, आपके रहते पार्टी काफी कमजोर हो गयी है।" जब देखा कि उनकी स्थिति मेरठ और ऋषिकेश से भी ज्यादा बदतर हो रही है, तो दिल्ली दरबार के लखनऊ आये चार सिपहसालारों के साथ वह भी दिल्ली कूच कर गये।

गोरखपुर केसरी वीर बहादुर सिंह ने दिल्ली पहुंचकर माखनलाल फोतेदार को पटा लिया है और एक दांव और खेलने की इजाजत ले ली। उन्होंने डगमगाते दिल्ली दरबार को झांसा दिया कि राजा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। संजय सिंह और लोकपति त्रिपाठी मेरे से ज्यादा दांव नहीं जानते। मैं राजा को ऐसा धोबीपछाड़ मारूंगा कि चित होते नजर आयेगा। देश की राजधानी से प्राण-दान लेकर लौटे वीर बहादुर सिंह ने असंतुष्टों को आतंकित करने का दांव शुरू कर दिया है। लेकिन राजा उनके दांव की काट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका शायद उनको अहसास नहीं। वीर बहादुर सिंह जता रह हैं कि वह असंतुष्टों से डरते नहीं। वह एक-एक कर उनकी छुट्टी कर रहे हैं। जफर अली नकवी, सुरेंद्र सिंह और सुनील शास्त्री के बारे में वह ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन राजा मांडा एक साथ धमाके न करके अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि एक-एक कर इस्तीफा दें, जिससे माहौल गर्म रहे, दिल्ली दरबार में असुरक्षा का भाव दिनोंदिन बढ़ता रहे।

उधर जबसे अमिताभ 'लावारिस' हुए हैं, दिल्ली दरबार में 'दोस्तों' पर कच्चे धागे से बंधी तलवार लटक गयी है। राजीव गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए बेचारे अमिताभ राजनीति के अंदर आये थे, लेकिन जब देखा कि उनके अंदर रहने से हाथ मजबूत होने के बजाय कमजोर हो रहे हैं, तो परम त्यागी अमिताभ बच्चन अपने दोस्त के हाथ मजबूत करने के लिए बाहर निकल गये। वह संगम में पवित्र होकर राजनीति में घुसे थे, लेकिन काजल की कोठरी के छोटे दरवाजे से घुटनों के बल बाहर निकले हैं। कितनी नामुराद है यह सियासत! कल 'शहंशाह', तो आज 'कुली' बनाते देर नहीं लगती।

अरुण सिंह ने जब देखा कि बोफोर्स की कीचड़ उनके दामन में लपेटने का सारा सरअंजाम हो गया है, तो उन्होंने दामन बचाकर निकलने में ही खैर समझी। झठ उन्होंने अपना मंत्री का तमगा उतारा और दिल्ली दरबार को थमा दिया। अब वह किस के साथ हैं, यह यक्ष प्रश्न जेठमलानी के प्रश्नों से भी ज्यादा जटिल है। लोग कह रहे हैं, वह विरोधी खेमे में हैं, लेकिन कपूरथला वंशज कह रहे हैं कि नहीं, हम राजीव गांधी के साथ ही हैं। अब कौन किसके साथ है या तो कंप्यूटर बता सकता है या इस समय राजनीतिक हिसाब-किताब रखने वाले हैडमुनीम फोतेदार बता सकते हैं।

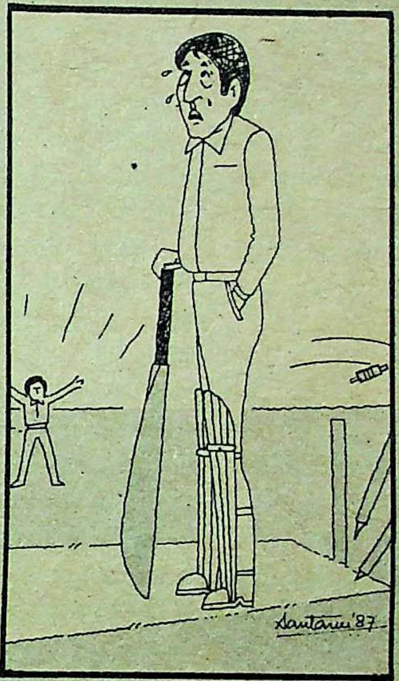

गेंद को जेठमलानी ने कलेक्ट किया और राजा को दिया। राजा अपने मार्ग पर आगे बढ़े, पीछे मुड़े, दौड़े, अंपायर पं०कमलापति त्रिपाठी को पार किया और...यह अमिताभ आउट...बिना खाता खोले। राजा ने यह गुगली फेंकी थी जो अमिताभ को समझ में नही आयी और वह अपना विकेट गंवा बैठे।

दोस्ती के स्वर्ण युग की समाप्ति के बाद वे लोग बहुत खुश हैं जो मंमी बना कर रख दिये गये थे। पुरानों की जवानी फिर अंगड़ाई लेने लगी है। कमलापतिजी को अपने 'लल्लू' की ओर मुख्यमंत्री की कुरसी दुल्हिनिया चाल से चलती नजर आ रही है। सत्ता के स्वंयवर में शामिल होने के लिए स्वयं उनमें भी नारदमोह का दौरा पड़ा हुआ है। ताईविहीन दादा को जयपुर के वातानुकूलित राजभवन में सत्ता का विरहताप बुरी तरह झुलसा रहा है।

ज्यों-ज्यों दिल्ली दरबार का पलस्तर उतर रहा है, त्यों-त्यों असंतुष्टों के सूने भवनों में शहनाई बजने लगी है। अब मौका आ गया है चुन-चुनकर बदला निकालने का। जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ पहाड़िया जैसे लोग लंगोट कस कर मैदान में ताल ठोंकने में लगे हैं। दो साल पहले दिल्ली दरबार का जो किल रणथंभौर के किले से भी मजबूत था, अब चूल-चू हिलने लगी है। पस्तहिम्मत दिल्ली दरबार का हौसला बढ़ाने के लिए टाइटलर और भगतजी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिहाड़ी पर जय-जयकार करने वाले लोगों को लाने की जिम्मेदारी अपने कंधो पर लाद ली है। जब भी दिल्ली दरबार को दिन में चांद-तारे दिखायी देने लगते हैं, तो उन्हें एक खुराक जिंदाबाद के नारों की गोर्बाचौफ की दोस्ती के पानी के साथ दे दी जाती है। लेकिन फिर किले का कोई हिस्सा टूट कर गिर जाता है और मर्ज बढ़ जाता है। लगता है मर्ज लाइलाज है!

जेठमलानी ने भी इस मर्ज को बढ़ाने कें कोई कोर कसर नहीं छोडी। भला बिना सिलेबस बताये, दिल्ली दरबार का इम्तहान लेना शुरू कर दिया। आजकल किसी परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ। फिर प्रश्न-पत्र में च्वाइस भी तो नहीं दी। १० में से १० सवाल करने के लिए कह दिया। भला ऐसा कभी होता है। यह सरासर नाइंसाफी है। दिल्ली दरबार का क्या कसूर रिजल्ट तो खराब होना ही था। फिर अजिताभ के मकान का मामला लीजिए। भई सन दो हजार तक सबको आवास मुहैया करना है। अपने प्रिय देशवासियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए अपना हक छोड़कर उन्होंने विदेश में अपना मकान बनवा लिया। देशवासियों के लिए उन्होंने यह त्याग किया है, लेकिन ऐसे त्यागी को गद्दार कहा जा रहा है।

दो साल में दिल्ली दरबार ने इतना देखा है, फिर भी लोगों को जो देखना चाहिए वह तो नहीं देखते और जो नहीं देखना चाहिए, वह देखने पर तुले हैं। ऐसे लोगों के कारण पता नहीं अभी उन्हें क्या-क्या देखना पड़ेगा।

बाल की खाल निकालने वाले लोग कहते फिर रहे हैं कि दिल्ली दरबार बार-बार कहते हैं कि हमने देखा है, लेकिन पता नहीं वह क्या देखते हैं? जब उनको अपने आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं, वही दिखायी नहीं पड़ता, तो देश में क्या हो रहा है उसे कैसे देखेंगे?

—दरबारी लाल

विद्या भैया की शामत

विद्याचरण शुक्ल बहुत दिनों से कांग्रेस-राजनीति की देहरी पर बैठे थे। उम्मीद यह थी कि उन्हें जल्दी ही अन्तःपुर तक प्रवेश मिल जायेगा। लेकिन हुआ यह कि देहरी भी गवा बैठे और अब सड़क पर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं।

उनके आकस्मिक दुर्भाग्य की कथा इस बार राष्ट्रपति चुनाव के साथ शुरू हुई। उम्मीदवार जब घोषित नहीं हुआ था, तब शुक्ल की गतिविधियां काफी दुस्साहसिक रहीं। विलिंगटन क्रिसेंट की एक कोठी और दक्षिण दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई अर्धगुप्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विपक्षी नेताओं को इतना उत्साहित करती रही कि उन्होंने संभावित अंतरिम प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में उनका नाम भी चला दिया। अब शुक्लजी कहते हैं कि नाम चलाने की शरारत हेमवती नंदन बहुगुणा ने की थी। फिर जो होना था, वही हुआ। कम्युनिस्ट ज्ञानीजी को सहयोग देने से मुकर गये, क्योंकि, मार्क्सवादी नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत के अनुसार ज्ञानीजी के पास कांग्रेस के ऐसे बीस सांसद भी नहीं थे जो उन्हें प्रस्तावित तथा समर्थित कर पाते। अब तक विख्यात हो चुके कम्युनिस्टों के विद्रोह के बाद विपक्ष का शीराजा बिखर गया और विद्याचरण शुक्ल ने अपने आपको जंगल में अकेले खड़े पाया। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हुआ और शुक्लजी की जन्मपत्री खोल दी गयी। इसमें केंडी नाम की युवती से उनका प्रेम प्रसंग, फिल्म अभिनेत्री विद्या सिन्हा से दुर्व्यवहार, इंटरनेशनल गोल्डन क्रेडिट कार्ड का घोटाला और एक फाइव स्टार होटल में आधी रात को हुआ हंगामा तक शामिल था। इस हंगामे में शुक्ल की खासी बदनामी हुई थी। विडंबना यह है कि शुक्ल के खिलाफ हाईकमान की कार्रवाई से जो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, वे अर्जुन सिंह नहीं, शुक्ल के सगे भाई श्यामाचरण शुक्ल हैं, जिन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके भाई की जगह पर उन्हें कांग्रेस में उनका पुनर्वास कर दिया जायेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पुनर्वास-अभियान में मध्यस्थता कर रहे हैं प्रकाश चंद सेठी जो खुद भी पुनर्वास के हिसाब से बहुत सुखमय नहीं हैं।

लाजवाब कल्पनाथ राय

कल्पनाथ राय का जवाब नहीं है। जितनी तेजी से वह अपनी भूमिकाएं बदलते हैं, उनसे लगता है कि वह फिल्मों में रहते, तो पता नहीं कहां पहुंच गये होते। उनकी ताजा सरगर्मी की शुरुआत तो एक अखबार में दिये गये उनके उस इंटरव्यू से हुई थी, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी को अनुभव-हीन, कृतघ्न और दंभी कहा था। इंटरव्यू छपा, इसके कुछ ही दिनों बाद कल्पनाथ राय कमलापति त्रिपाठी को पानी पी-पी कर कोसते नजर आये कि वह राजीव गांधी का साथ नहीं दे रहे हैं। फिर वह राशन-पानी लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीछे पड़ गये और एक ही सांस में उन्हें केजीबी और सीआईए का एजेंट घोषित कर डाला। इससे भी शांति नहीं हुई, तो एक दिन संसद के केन्द्रीय कक्ष में श्रीपति मिश्र और ए०पी० शर्मा पर बरस पड़े और फिर उस बरसने का जिक्र कांग्रेस के महासचिव नवल किशोर शर्मा से भी कर आये।

राष्ट्रपति चुनाव के दिनों उनकी दिक्कत यह थी कि उनको न संतुष्ट पूछ रहे थे और न असंतुष्ट। हर जगह उन्हें अछूत समझा जाता था। तो उन्होंने कोशिश यह की कि राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रस्तावकों या समर्थकों में उनका नाम दर्ज हो जाये। इस बारे में उनकी एक अर्जी भी कांग्रेस मुख्यालय में पड़ी हुई है, लेकिन उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी न हारने वाले राय ने अंत में राष्ट्रपति के लिए मतदान वाले दिन संसद भवन में जमा पत्रकारों को यह कहते हुए घेर लिया कि कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। लेकिन पत्रकार जब जमा हुए, तो राय ने भरपूर नाटकीय मुद्रा में कहा कि लोग चाहे जो कोशिश कर लें, कांग्रेस का प्रत्याशी भयंकर बहुमत से जीतने वाला है। इस 'रहस्योद्घाटन' से खीजे हुए पत्रकार जब उठने लगे, तो राय ने उनसे पूछा कि आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह का उतरा हुआ चेहरा देखा है? पत्रकारों ने कोई उत्तर नहीं दिया। राय को उत्तर चाहिए भी नहीं था।

उत्तर प्रदेश में दावत-युद्ध

उत्तर प्रदेश में इस समय भयंकर 'दावत-युद्ध' छिड़ा हुआ है। गुरिल्ला-शैली में लड़े जाने वाले इस युद्ध के एक मोर्चे पर हैं इंका के असंतुष्ट और दूसरे मोर्चे पर हैं संतुष्ट। इस युद्ध की एक झड़प १० जुलाई को देखने को मिली। उस दिन युद्ध का नगाड़ा जफर अली नकवी ने बजाया था। नौजवान और शाइस्ता राजनेता जफर नकवी वीर बहादुर मंत्रिमंडल में वन राज्यमंत्री हैं। उन्होंने उस दिन 'राजा मांडा' विश्वनाथ प्रताप सिंह के सम्मान में दावत का आयोजन किया था। 'राजा मांडा' वीर बहादुर की दृष्टि में 'विधर्मी' हैं और जो भी उनके साथ उठता-बैठता है, उसको वह इंका-धर्म को भ्रष्ट करने वाला मानते हैं। पहले भी एक-दो बार 'राजा मांडा' का स्वागत-सत्कार करके जफर इंका-धर्म विरोधी काम करने की गुस्ताखी कर चुके थे। लेकिन तब गनीमत यह थी कि इतने खुले तरीके से नहीं की थी। पर इस बार तो वह खुल्लमखुल्ला यह काम कर रहे थे। इसलिए वीर बहादुर सिंह को इसमें खुली बगावत और अपने नेतृत्व को साफ चुनौती की बू आयी। बस फिर क्या था, शुरू हो गया 'आपरेशन दावत विफल' अभियान। तुरंत नाकेबंदी की गयी। दस मंत्रियों को फरमान भेजा गया कि वे जफर के समानांतर दावतें आयोजित करें और अपने-अपने मंडल के इंका विधायकों को निमंत्रित करें, जिसमे कि कम-से-कम विधायक जफर की दावत में जा सकें। क्योंकि जफर की दावत में जाने का मतलब था वीर बहादुर के विरुद्ध खेमे में खड़ा होना। कम विधायकों के आने का मतलब था मुख्यमंत्री-विरोधी मोर्चे की हवा खुश्क होना, जिससे कि दीवार पर खड़े विधायकों का हौसला भी पस्त हो सके। लेकिन 'आपरेशन' उस समय फेल हो गया, जब जफर के यहां एक-दो नहीं, १०४ विधायक (जिनमें तीन विधान परिषद के सदस्य थे) पहुंचे। इस उपस्थिति का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि जो लोग अब तक झिझक रहे थे, वे भी निडर हो गये हैं। इस दावत के बाद ठहाके लगा-लगा कर कहा जा रहा है कि 'राजा मांडा' 'दांत दिखाने' लखनऊ नहीं आये थे, वीर बहादुर सिंह को 'आंखें दिखाने' आये थे। स्मरणीय रहे, राजा मांडा अपने बीमार दांत को दिखाने लखनऊ आये थे। लेकिन दिखाने के या खाने के, यह कहना मुश्किल है! वैसे जैसी स्थिति दिखायी दे रही है उससे यह लगता है कि राजा ने अब अपने असली दांत दिखाने शुरू कर दिये हैं। ■

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है"

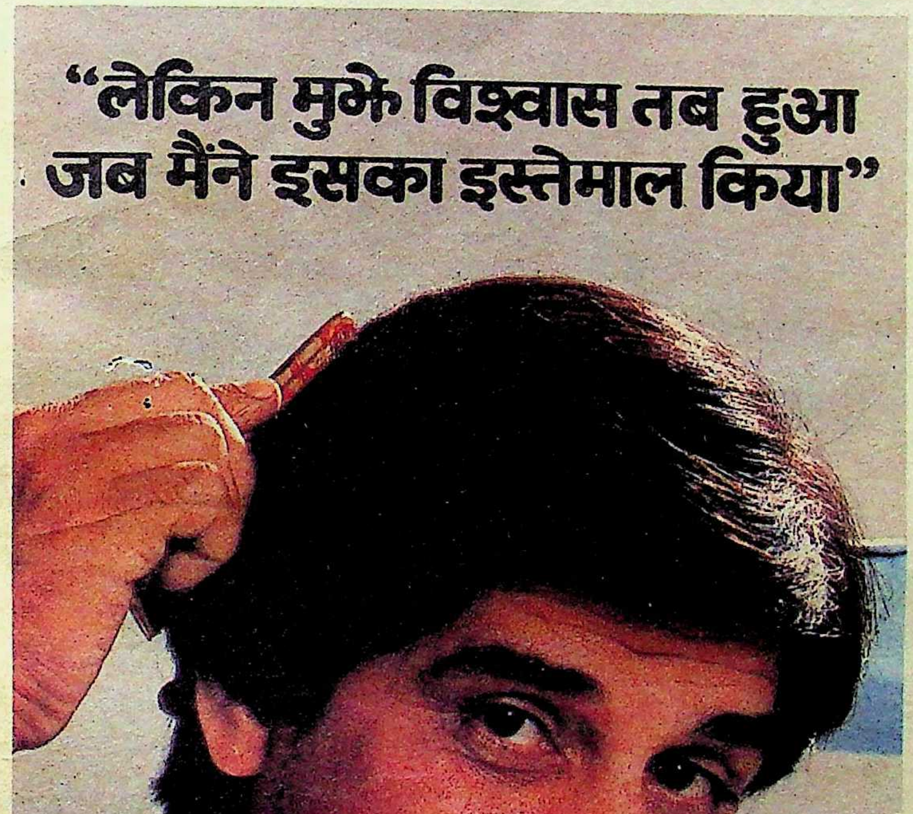

"लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रुसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश :

"सभी मामलों में रुसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
100 ml.
CONTAINING PROTEIN, VITAMINS AND CO-ENZYMES
DEY'S MEDICAL STORES LTD.

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

*यह श्रृंगार सामग्री नहीं है।

Dey's® की संभाल, आपका भरोसा

CLARION C-DMHV-3

छोटा मुसाफिर लम्बा सफर
हीरो है साथ, नहीं राहों में डर

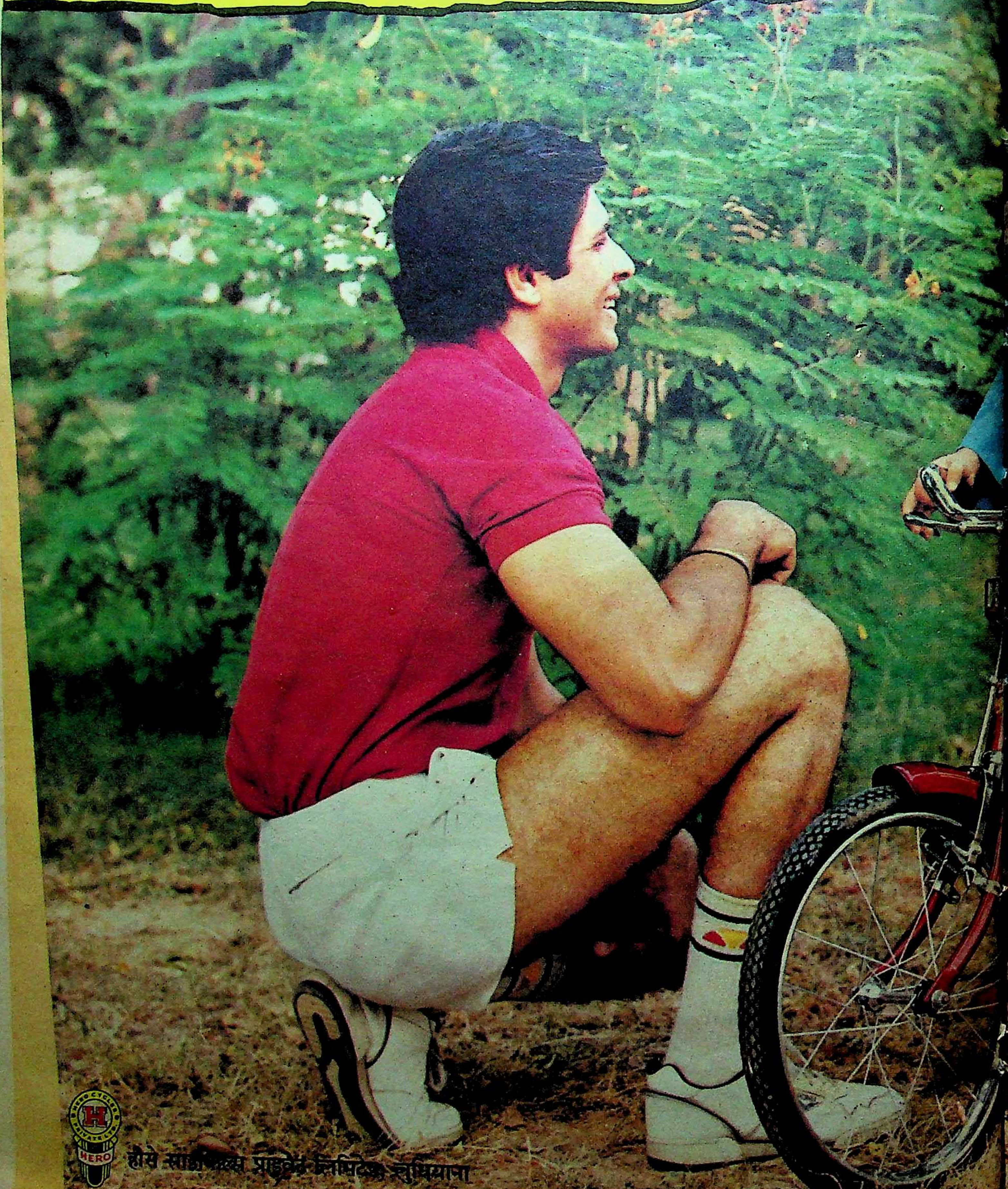
HERO CYCLES PRIVATE LTD.
HERO
हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना

हीरो मिनि राइडर *
४५ सै.मी. (ब्वॉय)

छोटे महाशय और नन्ही मैडम के लिए। स्कूल जाना हो, खेल हो या फिर ऐसे ही इधर उधर। बचपन के मीठे एहसास हीरो के साथ उम्र भर याद रहें।

भूरा, हरा, सिन्दूरी, लाल, काला या नीला, हीरो हर रंग में मन को भाए।

१६ मॉडल जिनमें पाँच बच्चों के लिए। गियर के साथ या बिना गियर। हर पसंद,हर साइज़ के लिए एक।

बच्चों की सवारी अब मम्मी पापा की परेशानी नहीं। देखने में छोटी लेकिन काम और गुण में बड़ी के बराबर।

हीरो स्किप्पर हाई-राइज़र
४० सै.मी.

हीरो रफ़-राइडर

हीरो
नन्हा राही
शान है शाही

दुनियाभर में नं० 1

1 HERO BICYCLES

हीरो अपनाएँ — नं० 1 होने का अनुभव पाएँ।

अब दुनिया की अधिकतम बिकने वाली साइकिल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स की ओर अग्रसर।

ा फ्लेवे *
सै.मी. (गर्ल)

* ब्वॉय व गर्ल मॉडल में उपलब्ध

HC-NP 200

देव आनंद और सोनम छाया: डी०आर० यादव

४७ वर्ष बड़ा ब्वाय-फ्रेंड

हालीवुड में ग्रेगरी पेक एवं रिचर्ड बर्टन तथा भारत में राजकपूर जब नाना-दादा लगने लगे हैं, उनके हमउम्र देव आनंद ६४ वर्ष की उम्र पा करके अभी भी 'पाठा' ही लगते हैं। पिछले दिनों देव आनंद अपनी नयी फिल्म के मुहूर्त पर जब अपने से ४७ वर्ष छोटी सोनम के साथ रोमांटिक सीन देने के लिए कैमरे के सामने खड़े हुए, तो इस नयी जोड़ी को देखकर लोग हैरत से ताकते रह गये। पांचवीं पीढ़ी की नायिका सोनम का कहना था, "देव साहब जैसा हॉट हीरो है कहां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में? पता नहीं, श्रीदेवी आंटी ने कैसे उनकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। देव साहब तो इतने गर्मजोश हैं कि उन्हें 'अंकल' कहने में भी शर्म लगती है, मैं तो उन्हें अपना फ्रेंड मानती हूं।"

४५ वर्षों में ११५ फिल्मों में नायक की भूमिका निभानेवाले देव आनंद ने १२ वर्षों के बाद खुद की निर्माण संस्था नवकेतन से बाहर की फिल्म 'लश्कर' बतौर नायक साइन की है और अपनी खुद की फिल्म 'सच का बोलबाला' खतम करने के बाद अपनी नयी फिल्म के लिए १५ वर्षीया हीरोइन की तलाश में हैं—नायक उनका बेटा सुनील नहीं, वह खुद होंगे। और तब सोनम को वह नयी हीरोइन दीदी और देव आनंद को 'हाटेस्ट ब्वाय फ्रेंड' बोलेगी, तो बेचारी सोनम के दिल पर क्या गुजरेगी भला?

किमी का दुख, किमी का गुस्सा

'टार्जन गर्ल' किमी कातकर सचमुच इन दिनों टार्जन बन गयी है। उसके भय से उसकी मां तक नहीं फटकती हैं उसके पास, बेचारे प्रोड्यूसरों की कौन कहे। 'सरफिरा' की शूटिंग के दौरान निर्माता-निर्देशक राज सिप्पी (जिनके प्रमुख सहायक गायकवाड़, 'सरफिरा' का निर्देशन कर रहे हैं) सेठ स्टूडियो आते ही सीधे माधवी के मेकअप रूम में घुस गये, पास खड़ी बेबी किमी के 'हलो' का जवाब भी नहीं दिया। सिप्पी के इस व्यवहार और मेकअप रूम के अंदर से आती हा-हा-हू-हू की आवाजें किमी के सीने पर बछियां चलाती रहीं। बात यहीं खतम होती तो गनीमत थी, सेट पर संजय दत्त जितनी देर रहा माधवी की बगल में कुरसी डाले बैठा उससे बातें करता रहा। और-तो-और सेठ स्टूडियो के दूसरे सेट पर शूटिंग कर रहे गोविंदा-मंदाकिनी भी आकर माधवी-संजय दत्त के पास जम गये। और एक कोने में कुरसी डाले किमी उन्हें देखकर कुढ़ती रही। उसकी कुढ़न कुछ इस हद तक बढ़ी कि जब उसके फिल्मी-नायक ('सिरफिरा' के) सुमीत सहगल ने उसे 'हलो' किया, तो उसने जवाब तक नहीं दिया, बेचारा सुमीत खिसियाता हुआ माधवी एंड पार्टी में जाकर शामिल हो गया। किमी ने इसी सुमीत सहगल के साथ पिछले वर्ष फिल्म साइन करने से मना कर दिया था कि इस नये छोकरे के साथ काम कर वह अपनी इमेज नहीं गिराना चाहती। लेकिन मजबूरी कि उसे चार बड़े बजट की फिल्में सुमीत के साथ ही करने को मजबूर होना पड़ा। किमी के दुख को भला कौन समझ सकता है!

किमी कातकर छाया: तैयब बादशाह

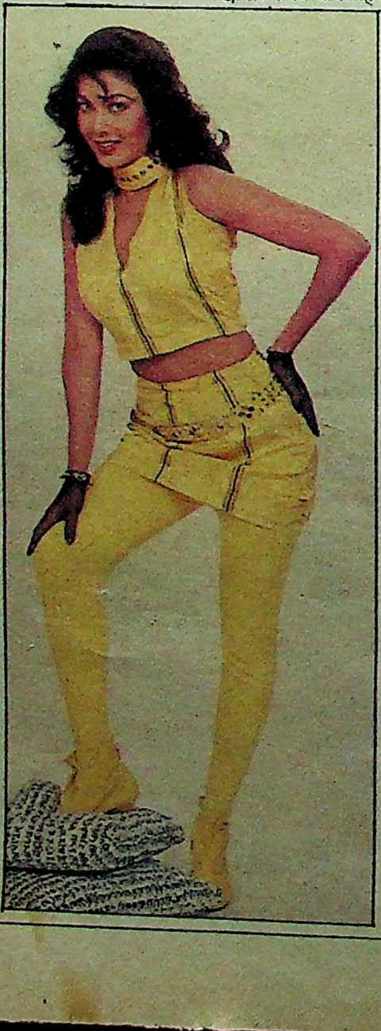

श्रीदेवी और अनिल कपूर छाया: तैयब बादशाह

बाक्स आफिस का माया-जाल

पिछले कई वर्षों से बंबइया फिल्म निर्देशकों को कौड़ी के मोल समझनेवाली श्रीदेवी को अब अपना विचार बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि अपनी ही सुपर हिट फिल्मों का हिंदी में री-मेक बनानेवाले दक्षिण के निर्देशक ही बाक्स आफिस का गणित जानते हैं और वहीं के फिल्म निर्माता हातिमताई की तरह रुपए खर्च करते हैं। उनकी इस 'आइडियोलॉजी' को बदला है फिल्म 'नगीना' और 'मिस्टर इंडिया' की अप्रतिम सफलता तथा एक फिल्म निर्माता के जवाब ने। 'नगीना' के बाक्स आफिस पर हिट होने पर जब एक बंबइया निर्माता उन्हें साइन करने पहुंचा, तो दक्षिण के निर्माताओं की कार्य पद्धति और पैसे खींचने में दरियादिली का बखान करते-करते श्रीदेवी ने जो राशि फरमाया उतने में वह विनोद खन्ना, रेखा और जयाप्रदा को साइन कर सकता था। लेकिन ढीठ निर्माता बोला, "जो राशि आप मांग रही हैं, उसमें दस (लाख) और जोड़कर पूरी राशि अभी नकद ले लीज़िए, लेकिन आपको लिखकर देना होगा कि जितनी डेट्स हमें जरूरत पड़ेंगी आप देंगी, शूटिंग कैंसिल नहीं करेंगी और आप से मिलने कोई भी सेट या लोकेशन पर नहीं आयेगा, चाहे 'वह' 'वही' (मिथुन?) क्यों न हो। न आप ड्रेस डिजाइनर के काम में मीनमेख निकालेंगी और न ही निर्देशक या किसी और के काम में। साथ ही अमिताभ बच्चन की तरह फिल्म के हिट हो जाने की गारंटी भी देंगी...।" श्रीदेवी का बिगड़ा दिमाग रास्ते पर आया या नहीं, पता नहीं। ■

राजा का इशारा

विश्वनाथ प्रताप सिंह को जब तक पार्टी से नहीं निकाला गया था, तब तक उनको अपने नेता का लिहाज था, अब जब दल से बाहर कर दिया गया है, तो वह सरकारी गोपनीयता की लक्ष्मण-रेखा को नहीं लांघ सकते। अन्यथा यह नहीं लगता कि राजा के पास भंडा फोड़ करने का मसाला नहीं है। दल से निष्कासित होने के बाद 'माया' पहली समाचार पत्रिका है, जिससे सिंह ने लंबी बातचीत की है। पचास मिनट की बातचीत में राजा सभी संबंधित मुद्दों पर बोले हैं, लेकिन बहुत सावधानी बरतते हुए। पर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने राजीव गांधी की आलमारी में बंद कंकालों की ओर इशारा न किया हो।

पनडुब्बी प्रकरण : जैसा कि सर्वविदित है, पनडुब्बी सौदों की जांच इसलिए करवानी पड़ी थी, क्योंकि प० जर्मनी स्थित राजदूत ने तार द्वारा सूचित किया था कि इस सौदे में सात प्रतिशत कमीशन दिया गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कहना है कि जब उनको यह सूचना मिली, तो उन्होंने अपने रक्षा विभाग में और फाइलें छानीं और फिर जांच का आदेश दे दिया। क्या सूचनाएं उनको और मिलीं, इसको राजा बताने में असमर्थता प्रकट करते हैं। क्योंकि वह गोपनीयता की शपथ तोड़ने के अपराधी नहीं बनना चाहते। जाहिर है, इस मामले के संबंध में सरकार के पास ऐसी सूचनाएं हैं, जिनसे इस पहेली का हल मिल सकता है। राजा भी इन सूचनाओं को दे सकते हैं, लेकिन अदालत में। पर क्या सरकार यह नौबत आने देगी? राजा को सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का है कि सरकार अब भी पनडुब्बी खरीदने में नहीं हिचक रही। इसका मतलब है कि सरकार को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि इस सौदे में दलाली खाने का गलत काम हुआ है और आगे भी होगा।

अजिताभ का मामला : वफादार कांग्रेसी राजा के खून के इसलिए प्यासे हैं, क्योंकि उन्होंने दलाली और स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा धन जमा करने का मामला उठाया था। अब जब एक दस्तावेज ने यह सिद्ध कर दिया है कि अजिताभ ने स्विट्जरलैंड में लगभग ८५ लाख का मकान खरीदा है, तो राजा कहते हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाये थे, उनकी पुष्टि हो गयी है। इसके साथ ही राजा एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वह यह कि राजीव ने यह बात कही थी कि यदि अजिताभ के खिलाफ कोई सबूत मिल जायेगा, तो वह तुरंत कार्यवाही करेंगे। सबूत मिल जाने पर तो कार्यवाही शुरू हो गयी, लेकिन एक अहम सवाल अभी अनुत्तरित है। वह सवाल अमिताभ और अजिताभ के इस दावे से खड़ा हुआ है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसको राजीव गांधी नहीं जानते हैं। इस कथन का राजीव गांधी ने भी खंडन नहीं किया है। अब जनता के सामने यह सवाल खड़ा है कि क्या राजीव यह जानते थे कि अजिताभ ने स्विट्जरलैंड में संपत्ति ले रखी है। क्योंकि आम लोग यह जानते हैं कि अजिताभ राजीव गांधी के पारिवारिक मित्र हैं। लेकिन यह समझ के बाहर है कि अमिताभ और अजिताभ किस आधार पर यह कहते रहे हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे थे, उसको राजीव गांधी जानते थे। कुछ हलकों में दोनों भाइयों के इस दावे को शंका की नजर से देखा जाता है। बहरहाल, इस दावे के कारण ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजीव भी इस दलाली के कीचड़ में सने हैं। यही वह आरोप है, जिसके आधार पर राजीव गांधी पर मुकदमा चलाने की मांग की जा रही थी। इसे परिस्थितिजन्य सबूत माना जा रहा था। इसीलिए राजा कहते हैं कि राजीव अपनी स्वच्छता के लिए यह साबित करें कि वह अजिताभ का यह कारनामा नहीं जानते थे।

राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि आगे चलकर अजिताभ यह कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में उनके पास 'बेनामी' संपत्ति है—यानी उनके किसी विदेशी दोस्त या नियोजक ने उनको यह खरीद कर दी है, असली मालिक वह नहीं हैं। 'बेनामी' संपत्ति का अजीब प्रावधान केवल भारतीय कानून में ही है, बाहर के मुल्कों में ऐसा कोई कानून नहीं है। राजा से जब यह सवाल किया गया, तो उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि वह मौका आने तो दीजिए। जाहिर है जब 'बेनामी' की बात आयेगी, तो सवाल यह भी उठेगा कि आखिर इतनी भारी 'भेंट' उनको किस उद्देश्य से दी गयी? बहरहाल, ये बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन [illegible] प्रताप सिंह ने 'माया' से अपने साक्षात्कार में जो संकेत दिये हैं, वे आगे चलकर कोई राज दिखा सकते हैं। प्रस्तुत है अगले पृष्ठों में उनका [illegible]

साक्षात्कार/विश्वनाथ प्रताप सिंह

प्रधान मंत्री बतायें कि वह अजिताभ का मामला जानते थे या नहीं ?

माया : आपको 'कैशियस' और 'ब्रूटस' (रोमन सम्राट सीजर के खिलाफ षड्यंत्र के अगुआ) कहा गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंह : मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की है।

माया : आपको ऐसा कहना बुरा नहीं लगता ?

सिंह : एक महीने तो मुझे महसूस हुआ, इसके बाद मैंने अपने से पूछा कि यह सब मैंने अपने लिए किया है या उसूलों के लिए। मुझे उत्तर मिला 'उसूलों के लिए', तब से मुझे लगा कि वी०पी० सिंह के लिए जो कुछ कहा जाता है, वह अप्रासंगिक है।

माया : कल्पनाथ राय ने 'माया' को कहा है कि 'वी०पी० सिंह गद्दार है, उसका पिता गद्दार था और दादा भी गद्दार था।' आपकी जब प्रेस कांफ्रेंस हो रही थी, तब उन्होंने आपके घर के तीन चक्कर लगाये। उन्होंने 'माया' के विशेष संवाददाता को पकड़ कर पूछा, "राजा क्या कह रहा है ?" क्या आप ऐसी बातों से आहत नहीं महसूस करते ?

सिंह : यह कल्पनाथ राय की राय है। यह उनकी राय है, उनकी दौलत है, इसको वह संभालें। जब तक मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तब तक यह मेरी दौलत नहीं बनती।

माया : क्या आप उनको कोई जवाब देना नहीं चाहते ?

सिंह : मैं उनको क्या जवाब दूं, किस बात का जवाब दूं ?

माया : आपको वह गद्दार बता रहे हैं।

सिंह : व्यक्ति स्वयं अपने और अपने देश के लिए जिम्मेदार होता है। देश और स्वयं के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता। किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति के देश के बारे में किसी को प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। मैंने जो कुछ किया है, वह देश के हित की रक्षा करने के लिए देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर किया है। मैंने आर्थिक अपराधियों और रक्षा-सौदों के दलालों के खिलाफ कार्यवाही की है और जो देश की संपत्ति को लूट कर स्विट्जरलैंड में ढेर करते हैं, उनको बेनकाब किया है। अब वह सब कुछ साबित भी हो गया है। जब बोफोर्स रिपोर्ट आयी, तो कुछ पार्टी सदस्य मुझ पर चढ़ बैठे थे। लेकिन उसका आदेश तो स्वयं सरकार ने दिया था और परिणामस्वरूप ५० करोड़ के भुगतान की बात साबित हुई थी। इससे मेरी बात की पुष्टि हो गयी। ज्योंही यह सबूत मिला कि स्विट्जरलैंड में अजिताभ की संपत्ति है, तो स्वयं प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ जांच पर दस्तखत किये। इससे फिर मेरी बात की पुष्टि हो गयी। हालांकि इसके कारण मुझे अपनी राजनीतिक जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन मेरे उसूलों की जीत हुई और मैं सही निकला कि रक्षा-सौदों में रिश्वत चली है एवं कार्यवाही होनी चाहिए। मेरी यह बात भी सही निकली कि स्विट्जरलैंड में प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्ति है और इसके खिलाफ कदम उठाये जाने चाहिए। मेरे निष्कासन से एक दिन पहले तक मैंने कोई पार्टी-विरोधी काम नहीं किया। जी०के० मूपनार ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठता। यहां तक कि मेरा इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया। जब मैंने कहा कि अजिताभ की स्विट्जरलैंड स्थित संपत्ति की जांच की जानी चाहिए, तो २४ घंटे के भीतर-भीतर मुझे बाहर फेंक दिया गया। अजिताभ बच्चन के खिलाफ जांच के नतीजों को नजर अंदाज किया जा सकता है, लेकिन जिस आदमी ने जांच की मांग की, उसको पूरी तरह पार्टी से काट कर फेंक दिया।

माया : आप ढाई साल तक वित्तमंत्री रहे हैं और बिना वित्त मंत्रालय के कोई रक्षा-सौदा नहीं हो सकता। आपने उस दौरान कोई जांच क्यों नहीं करवायी ?

सिंह : मेरे वित्त मंत्रालय में आने से पहले ही पनडुब्बी-सौदा हो चुका था। इस सौदे के बारे में एक चीज है जो हमें पूछनी चाहिए कि जो नयी पनडुब्बियां खरीदी जा रहीं हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है ? क्या कमीशन दियां जा रहा है या बंद कर दिया गया है ? तकनीकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय में नहीं आती। वित्त मंत्रालय में यह कोई कैसे जान सकता है कि कब भुगतान होने जा रहा है ? मेरे कार्यकाल में सारी फाइलें प्रधानमंत्री के अनुमोदन से आती थीं जो रक्षामंत्री भी थे। जब किसी फाइल पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह किसी भी काबीना मंत्री के लिए स्वीकार करने के लिए काफी होता है।

माया : पनडुब्बियों की जांच के लिए आप इतनी जल्दी में क्यों थे ? ऐसे मौके पर आपने आदेश क्यों दिये। क्या कोई खास बात थी ?

सिंह : नहीं, पश्चिम जर्मनी स्थित हमारे राजदूत ने तार भेजा था कि ७ प्रतिशत का भुगतान हुआ है।

माया : क्या यह बताया गया था कि यह किसको भुगतान हुआ ?

सिंह : नहीं, यह नहीं बताया। रक्षामंत्री के रूप में मुझे जो सूचनाएं मिली हैं, उनको मैं नहीं बता सकता।

माया : लेकिन आपके पास सूचनाएं थीं ?

सिंह : मैं उनको बता नहीं सकता। यह तो सरकार पर है कि वह बताये कि क्या हुआ था। ज्योंही तार मिला, तो मैंने विभाग में और सूचनाओं को तलाशा, तब मैंने जांच के आदेश दिये। इसको फेयरफैक्स से जोड़ने का कोई मतलब नहीं। यह फेयरफैक्स के मामले के २४ दिन पहले की बात है।

माया : राजीव गांधी कहते हैं कि बोफोर्स के शिष्टमंडल को बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे कोई सूचना नही मिलेगी।

सिंह : मैं इससे बिलकुल असहमत हूं। सारा देश इसको लेकर चिंतित है, इसलिए हमको बोफोर्स पर हर संभव दबाव डालना चाहिए। बोफोर्स ने उस समय कहा था कि हम अपने ग्राहकों को नाम बता देंगे। अब हमें उनको अपने वचन का पालन करवाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि यदि हम बोफोर्स पर दबाव डालें, तो वे अपने पिछले बयान का पालन करेंगे। उनको अपने दलाल को जो भुगतान करना था, कर दिया। अब दलाल से कोई मतलब नहीं। अभी १७०० करोड़ रुपए में से केवल ३०० करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, बाकी १४०० करोड़ रुपए का अभी भुगतान करना है। यह भुगतान रोक लीजिए। यह राशि सरकार के पास जोरदार हथियार है। लेकिन अरुण सिंह के इस्तीफे से यह बात साफ हो गयी है कि उन जैसे योग्य तथा ईमानदार मंत्री जो प्रधानमंत्री के दोस्त भी रहे हैं, अपना कर्तव्य ठीक से निभाने में असमर्थ हैं।

माया : क्या यह बोफोर्स का मामला पनडुब्बियों के मामले से भी बड़ा है ?

सिंह : हो सकता है। लेकिन सवाल ३० करोड़ रुपए का नहीं है, सवाल तो यह है कि पनडुब्बियों के सौदे में क्या सरकार और धन यों ही जाने देगी ? मतलब यह कि क्या पनडुब्बियों के लिए सरकार और पैसे देने के लिए तैयार है ?

माया : आपने स्विस बैंक विवाद की जांच के आदेश क्यों नहीं दिये। 'प्रोब इंडिया' पत्रिका ने भी इसके संबंध में कुछ छापा था ?

सिंह : इस पर अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं। वित्तमंत्री के रूप में मैं नहीं जान सकता था कि किस स्तर पर कौन क्या कर रहा है। वित्तमंत्री के रूप में रोजाना मेरे पास करने को केवल यही काम नहीं था।

माया : क्या यह सरकार के लिए अपमानजनक नहीं है कि एक निजी एजेंसी ने अपेक्षित जानकारियां हासिल कर लीं, लेकिन सरकार असफल रही ?

सिंह : यदि मैं वित्त मंत्रालय में होता, तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब दे सकता था।

माया : यदि इस सरकार के साथ आप वित्त मंत्रालय में होते, तो अजिताभ बच्चन के मामले में आप क्या करते ?

सिंह : दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि के बाद मैं अजिताभ को गिरफ्तार कर लेता। एक बार यह सत्यापित हो जाये कि दस्तावेज सही हैं, तब आपको बड़ी तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए।

माया : अमिताभ तो इस बात से इनकार करते रहे हैं कि विदेशों में उनका धन जमा है।

सिंह : मैं नहीं जानता कि इसकी वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है ? लेकिन यदि 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित दस्तावेज सही है, तो यह 'फेरा' उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य भी एक गंभीर मामला है कि बच्चन बंधुओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि बच्चन-बंधुओं ने कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया, वह प्रधानमंत्री की जानकारी में किया है। अब यह दस्तावेज सामने आ गया है। प्रधानमंत्री को अपने को स्वच्छ साबित करने के लिए बतलाना चाहिए कि वह इसे पहले से जानते थे या नहीं।

माया : भय यह है कि यदि अजिताभ पर मुकदमा चलता है, या जांच होती है, तो वह कह सकता है कि 'बेनामी सौदा' है और वह इस देश के किसी भी व्यक्ति को फंसा सकता है।

सिंह : मैं नहीं जानता। मामले को इस हद तक तो आने दो।

माया : जैल सिंह ने आपको कायर कहा था। क्या आप स्वय को ऐसा मानते हैं ? क्योंकि आपने सत्ता संभालने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

सिंह : सार्वजनिक जीवन में आपको सिद्धांतवादी होना पड़ेगा। अवसरवादी होना साहस नहीं, कायरता है।

माया : आप अपने मिशन को क्या कहेंगे ?

सिंह : यह मेरा नहीं, जनता का मिशन है। वो कुछ उत्तर चाहती है, वह चाहती है कि कुछ मामलों में जांच हो। वह सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ देखना चाहती है। हमें इसका उत्तर देना है।

माया : क्या आप समझते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया ?

सिंह : संभवत : यह भी एक कारण रहा हो।

माया : आपकी पार्टी के लोग यह कहते रहे हैं कि आप पार्टी और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे ?

सिंह : मैंने तो आर्थिक अपराधियों के खिलाफ पार्टी की नीतियों को ही लागू किया है। क्या अमिताभ बच्चन के कारनामें देश को अस्थिर नहीं कर रहे हैं ? हम आर्थिक अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सरकार की साख को कायम किया जा सके।

माया : क्या आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कल्पनाथ राय ने 'अस्थिर करनेवालों' में अजिताभ का नाम नहीं लिया ?

सिंह : मैं नहीं जानता कि अजिताभ से उनके क्या रिश्ते हैं।

माया : पांच वर्ष पूर्व जब आपने 'त्याग पत्र' दिया था, तब आपने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको टिकट दिया था और आप उनके प्रति वफादार रहेंगे। क्या अब भी आप मानते हैं कि आप उनके प्रति वफादार हैं ?

सिंह : मैंने अपना त्याग पत्र इस शर्त पर भेजा था कि यदि यह पार्टी के लिए उपयोगी हो, तो इसे स्वीकार कर लिया जाये।

माया : तो क्या आप ऐसा नहीं मानते कि आपने पार्टी के साथ दगा किया ?

सिंह : अंतिम क्षणों में मैं अपना सिर तक देने को तैयार था।

माया : क्या आप ऐसा नही मानते कि आपने श्रीमती गांधी की स्मृति के साथ धोखा किया ?

सिंह : नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं, मैंने जो कुछ किया है, वह श्रीमती गांधी की स्मृति में सहायक होगा। लेकिन क्या आप ऐसा समझते हैं कि अजिताभ के काम और यह बोफोर्स सौदा, ये सब क्या राजीव और इंदिरा गांधी के लिए सहायक होंगे ?

माया : आपके हिसाब से कैसे हालात बन गये हैं।

सिंह : उनके (अजिताभ) उन कर्मों ने श्रीमती गांधी की स्मृति को चोट पहुंचाई है, हमें उसकी रक्षा करने में सहयोग करना चाहिए।

माया : क्या आप समझते हैं कि सरकार विन चड्ढा का पता लगाने में कामयाब हो सकेगी ?

सिंह : विन चड्ढा इस देश से बाहर जाने में कामयाब हो गया और जब वह विदेश में था, तो वह हमारे दूतावास में आकर अपनी संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुख्तारनामे (पावर आफ अटर्नी) का सत्यापन कराकर ले गया। वह हमारे दूतावास में आता है और वहां से चला जाता है- फिर आप लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि आप विन चड्ढा को ईमानदारी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

माया : क्या आप ऐसा नहीं मानते कि हमने खुद को ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया है कि कोई भी हमें 'ब्लैकमेल' कर सकता है ?

सिंह : इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राय: हर देश सूचनाएं प्राप्त कर लेने की कोशिश कर रहा होगा। हमने गलत काम करके खुद को उनका निशाना बना लिया है।

माया : आपके अनुसार किस प्रकार का संघर्ष आपके सामने है ?

सिंह : मैंने उन मुद्दों का निर्धारण कर लिया है, जिन्हें मैं जनता के बीच ले जाऊंगा।

माया : क्या आपको लगता है कि व्यावसायिक क्षेत्र से धन लिये बगैर आप यह लडाई लड़ने में कामयाब हो सकेंगे ?

सिंह : मैं व्यावसायिक क्षेत्र से कोई धन नहीं लूंगा।

माया : तब आप कैसे लड़ेंगे और कैसे बाहर निकलेंगे।

सिंह : हमें इतने लंबे समय तक धन की जरूरत नहीं पड़ी। हम जनता को संगठित करेंगे।

माया : क्या आप इस रूसी-वक्तव्य से चिंतित नहीं हैं कि सरकार की समस्याएं जल्दी ही दूर हो जायेंगी। इसका मतलब है, रूसी इस सरकार के साथ खड़े हैं, जिसके विरुद्ध आपने मामले उठाये हैं।

सिंह : मैं क्यों चाहूंगा कि सरकार परेशानी में पड़े। लेकिन ये समस्याएं तभी दूर होंगी, जब जनता आश्वस्त हो जायेगी।

माया : आपकी ईमानदारी पर दाग लगाने का जो अभियान चल रहा है, क्या उससे आप आशंकित हैं ?

सिंह : अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है।

माया : इसका मतलब है, आपने खुद को जनता के हवाले कर दिया है। क्या आपको भरोसा है कि आपको जनसमर्थन मिल रहा है ?

सिंह : हां, इस दिशा में मैं काफी आगे बढ़ गया हूं।

माया : तो क्या आप भविष्य के प्रति आशावान हैं ?

सिंह : मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं तो देश और उसके लिए संघर्षरत जनता के भविष्य के प्रति चिंतित हूं। यदि आप मुझे मार दें या नष्ट कर दें तो भी जनता का संघर्ष रुकनेवाला नहीं है। अब खुद वी०पी० सिंह भी इसे रोकना चाहें, तो भी यह नहीं रुकेगा। जनता आश्चर्यचकित है कि कड़ी मेहनत से अर्जित धन आखिर जा कहां रहा है ? वह स्विट्जरलैंड क्यों जा रहा है ? यदि आप इसका उत्तर यह देते हैं कि वी०पी० सिंह शरारत कर रहा है, तो यह कोई उत्तर नहीं है। वी०पी० सिंह कुछ भी होगा, जनता तो बस यह जानना चाहती है कि उसका धन किधर चला गया। जनता कुछ पूछ रही है, अधिकारी कुछ और ही बता रहे हैं। इससे जनता कैसे संतुष्ट होगी ?

माया : क्या आपको प्रधानमंत्री से अपना संबंध तोड़ने पर खेद है ?

सिंह : हां, मुझे खेद है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिछले २० सालों से मेरा निकट का संबंध रहा है।

माया : लेकिन आपने राजीव गांधी के साथ भी तो वर्षों काम किया है।

सिंह : हां। इस दृष्टि से मुझे खेद है, लेकिन...

माया : लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि कर्तव्य के सामने व्यक्ति को अपने मित्र, संबंधी और यहां तक किसी का भी त्याग कर देना चाहिए ?

सिंह : हां।

माया : क्या आप ऐसा नहीं मानते कि आपने राजीव गांधी को धोखा दिया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह आप पर बड़ा भरोसा रखते थे ?

सिंह : सार्वजनिक जीवन में मित्रों का नहीं, जनता का विश्वास महत्वपूर्ण होता है। जब दो निष्ठाएं आमने-सामने हों, तो उनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। राजीव गांधी और मेरे रास्ते अलग-अलग हुए, क्योंकि मतभेद मुद्दों को लेकर थे। इन अर्थों में मैंने राजीव को नीचा नहीं दिखाया।

माया : ऐसा कहा जाता है कि आप और राजीव के बीच सोच-समझकर मतभेद पैदा करने के प्रयास होते रहे थे।

सिंह : मैं अब इस पर टिप्पणी क्यों करूं ?

माया : क्योंकि राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, इसलिए जिस तरह से ये सब बातें हुईं, क्या उससे आप दु:खी हैं ?

सिंह : व्यक्तिगत रूप से राजीव के लिए मुझे खेद है।

माया : बच्चन-प्रसंग पर आपकी टिप्पणी ?

सिंह : मेरा एक उद्देश्य तो उसी क्षण पूरा हो गया, जब श्री गांधी ने अजिताभ बच्चन के विरुद्ध जांच-आदेश पर हस्ताक्षर किये। मैं कह सकता हूं कि हिसाब बराबर हो गया। आखिरकार, भूरेलाल और विनोद पाण्डेय को यही जानने के लिए ही तो अपमानित और उत्पीड़ित किया गया था कि क्या बच्चन बंधुओं के खिलाफ कोई जांच हो रही है ? वे बेचारे बिना बात परेशान किये गये। अब वे निर्दोष साबित हो गये हैं।

राजीव के खिलाफ राजा का युद्ध शुरू

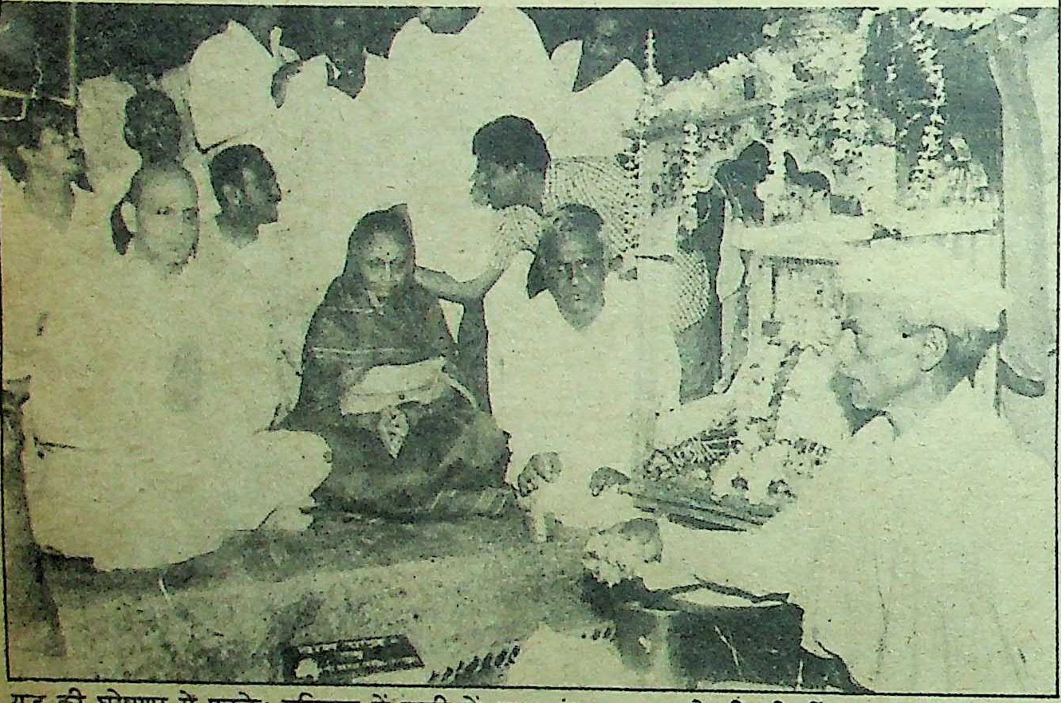

युद्ध की घोषणा से पहले: हरिद्वार में पत्नी के साथ गंगा-पूजा करते वी०पी०सिंह

अपूर्व नाटकीयता भरा दिन था। एक बार शंका हुई, कल्पनाथ राय ठीक तो हैं?, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया?

१, तीन मूर्ति मार्ग के बंगले से विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रेस कांफ्रेंस के बाद निकलनेवाले कुछ पत्रकारों ने देखा कि सफेद मारुति में बैठे कल्पनाथ राय ने १० मिनट में तीन चक्कर लगाये। वह फाटक के पास आकर गाड़ी रोकते थे, अंदर झांकते थे और फिर मोड़कर सड़क के दूसरी ओर खड़ी कर देते थे।

इस संवाददाता को उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया। पूछा, "आप पी०टी०आई० (अंग्रेजी संवाद समिति) के हैं? अच्छा, 'माया' के। अच्छा बताइए तो राजा...क्या कह रहा है?" हाथ पकड़-पकड़कर उन्होंने लगभग जबरन यह सुना कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा, फिर हम तीन संवाददाताओं को अपनी कोमलांगी कार में भरकर आरिफ मोहम्मद खां के घर के सामने छोड़ा। रास्ते भर अपने प्रिय विषय पर उनका प्रवचन चालू रहा, "इसके बाप गद्दार थे, दादा गद्दार थे, यह भी गद्दार है।"

अब बरदाश्त नहीं करेंगे? : हरिद्वार में आरिफ

ठीक दो घंटे पहले इन्हीं कल्पनाथ राय को विद्या चरण शुक्ल संभवतः उनके जीवन का सबसे शानदार सम्मान दे चुके थे। राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित अपने राजसी निवास में पत्रकारों से खचाखच भरे विशाल कमरे में शुक्ल ने घोषणा की, "मैं पार्टी-नेतृत्व में परिवर्तन चाहता हूं, संगठन में भी और संसदीय दल में भी।"

उनसे पूछा गया, "आपकी दृष्टि में नेतृत्व के लिए बेहतर विकल्प कौन है।" उत्तर था, "कल्पनाथ राय बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मैं राजीव गांधी की अपेक्षा कल्पनाथ राय को नेता मानना पसंद करूंगा। या फिर के०के० तिवारी को।"

उसी दिन पूर्वान्ह का एक रोचक दृश्य था, प्रधानमंत्री निवास—७, रेसकोर्स रोड में। सफेद कुर्ते-पाजामें में लंबे-चौड़े अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री कक्ष से निकल कर आये थे और अकेले चल रहे थे अपने लंबे डग भरते। झुका चेहरा देखकर चार-पांच कदम पीछे चल रहे अमेठी के पत्रकार कवि-कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश पीयूष ने टिप्पणी की कि सुपर स्टार कुछ उदास, बुझे से लग रहे थे। उत्तर था कि इसमें सफल अभिनेता के चेहरे की एक झलक में अंतर्मन पढ़ने की चेष्टा व्यर्थ है।

सामने ही अमिताभ ने गले में लटकता टोकन उतारकर एक सुरक्षाकर्मी को दिया और प्रधानमंत्री निवास के स्वागत कक्ष में उन्हें घुसते देख उमड़ती भीड़ से बचकर बगल के दरवाजे से निकले, बाहर एक सामान्य-सी गहरे रंग की फियट में बैठे और चले गये।

शाम को सूचना आयी कि अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।

उसी शाम पांच बजे विश्वनाथ प्रताप सिंह की बैठक में घमासान माहौल था। देशी-विदेशी

पत्रकार, फोटोग्राफर, विदेशी टेलिविजन एजेंसियों के लोग अपने कैमरे-माइक्रोफोन सजाये बैठने या खड़े होने की जगह के लिए संघर्षरत थे। पीछे के लोग कुर्सियों पर खड़े थे, आगे-वाले कालीन पर बैठे थे, बाकी दायें-बायें और पीछे खड़े थे। इस सबके बीच में बैठे थे, राजा साहब।

उन पर शब्दशः प्रश्नों की बौछार हो रही थी। और वह एक ही ढाल के पीछे बार-बार शरण लेते थे, कभी हसंकर, कभी उग्रता के साथ, "मैंने कोई प्रेस-कांफ्रेंस नहीं बुलायी थी। पार्टी अध्यक्ष को लिखे मेरे पत्र का उत्तर अभी नहीं आया है। जब तक यह तय नहीं हो जाता कि मैं कांग्रेस में हूं या नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तब तक मेरा पत्र पढ़िए और समझिए।"

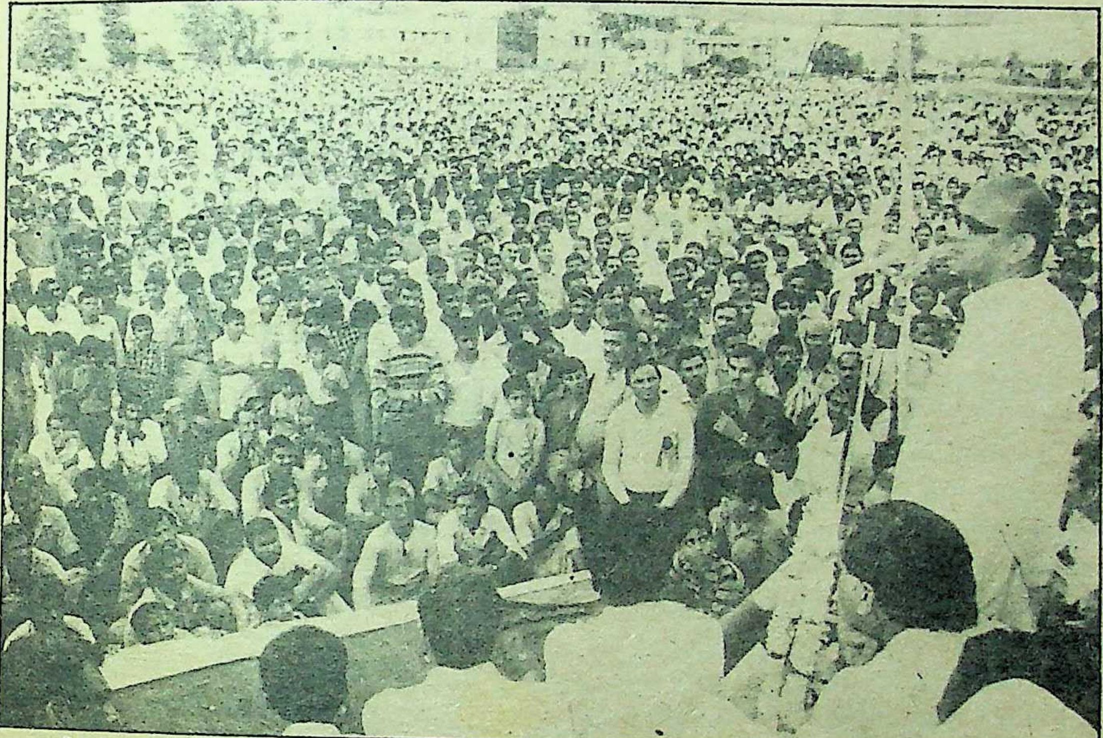

आप ही फैसला करें: हरिद्वार में जनता को जगाते हुए वी॰पी॰सिंह

किंतु एक घंटे बाद ही राजा साहब की यह सतर्कता ढीली पड़ चुकी थी। तब वह आरिफ मोहम्मद खां की किताबोंभरी बैठक में अरुण नेहरु, विद्याचरण शुक्ल, आरिफ और सत्यपाल मलिक के साथ बैठे थे। यह बैठक भी खचाखच भरी थी। फटा कुर्ता और दुखती बांह लिये आरिफ पिछले दो घंटों की उत्तेजना की प्रतिक्रिया में तमतमाए, किंतु शांत बैठे थे।

उन पर लगभग सवा पांच बजे हमला हुआ था। (देखें बाक्स)। साढ़े पांच-पौने छह बजे अरुण नेहरू अचानक पत्रकारों से घिरे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास पहुंचे थे और दस मिनट बाद उन्हें लेकर आरिफ के घर लौट गये थे। पीछे-पीछे पत्रकारमंडली पहुंची, तो आरिफ के बंगले के सामने सड़क पर दोनों ओर कारों-स्कूटरों की पंक्ति थी, फुटपाथ पर पुलिसवालों की और अंदर प्रांगण में पत्रकारों, समर्थकों की भीड़। उसके बीच में पसीने से तर-बतर, उत्तेजित आरिफ बैठे गले से बता रहे थे, हमले का घटनाक्रम—कि कैसे उनके पुलिस अंगरक्षकों ने खुद चोट खाकर उन्हें बचाया, वरना शायद उन्हें मार ही दिया जाता। पूरी हवा में सनसनी थी।

वी॰पी॰ सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ के साथ अंदर गये, थोड़ी देर में बाहर आये और नेहरू ने घोषणा की, "हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। सांसदों की सुरक्षा की उनकी भी जिम्मेदारी है। आधे घंटे बाद दोनों लौटे और एक बार फिर आरिफ के कमरे में प्रेस कांफ्रेंस जम गयी। उसी के बीच में अपनी हल्की नीली मर्सिडीज में आ गये थे, विद्या चरण शुक्ल।

एक घंटे पहले के सतर्क, सावधान राजा साहब उस समय कह रहे थे, "यह (हमला) राजनीति का अपराधीकरण है। बंदूक की नली और शारीरिक बलप्रयोग से असहमति को दबाने का प्रयास है। यह पूर्वनियोजित था। अन्यथा उस विशेष सुरक्षा क्षेत्र में, जहां गृहमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं, तीन घंटों में दो बार हमला हो और पुलिस रोके नहीं, यह कैसे संभव है? जब सांसदों का यह हाल है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा?"

बीच-बीच में अरुण नेहरू के बाण छूट रहे थे, "हमला करने आनेवालों को दोष देने बेकार है। दोष उनको आदेश देनेवालों का है। उन्हें किसने भेजा? यह अर्जुन सिंह से पूछिए, या आनंद शर्मा से, या सुरेश पचौरी या डी॰पी॰ राय से। सबसे अच्छा तो पार्टी अध्यक्ष से पूछिए।...भय का अस्तित्व उनके लिए है जो डरते हैं। इस तरह का काम एक कायर ही करता है।...प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठा दिखाने के इससे बेहतर भी तरीके होंगे।...रामधनजी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।"

प्रेस-कांफ्रेंस खतम होते-होते वहां उ॰प्र॰ के भूतपूर्व मंत्री श्रीकृष्ण गोयल और चार-पांच अन्य कांग्रेसी विधायक आ चुके थे। आरिफ के मित्र, पत्रकार जैसे-जैसे खबर पाते थे, चले आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के मंत्री अम्मार रिजवी को हरा कर ताजा-ताजा विधायक बने अकबर अहमद डम्पी काफी पहले से उपस्थित थे। लोकदल के एक नेता वहां पधार चुके थे और कमरे में बंटते लड्डुओं के बीच एक कोने में खड़े होकर एक पत्रकार को आरिफ पर हुए हमले पर अपनी भर्त्सना लिखवा रहे थे।

एक सनसनी-भरा दृश्य उसी समय एक किलोमीटर दूर तुगलक रोड थाने पर भी था। डेढ़-दो सौ युवक कांग्रेस कार्यकर्ता थाने की लाल जमीन पर दरी पर बैठे नारे लगा रहे थे, "आरिफ चोर हाय-हाय, आरिफ कुत्ता हाय-हाय, आरिफ को गिरफ्तार करो।"

तेज घटनाचक्र: इसके बाद तो घटनाचक्र अद्भुत तेजी से घूमा। १८ जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस ने एक धमाका किया। संपादक अरुण शौरी के नाम से खबर छपी थी, जिसमें फोटो थी, स्विस सरकार के एक दस्तावेज की, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि स्विट्‌जरलैंड के जिस मकान में अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ रहते हैं, वह उनकी अपनी संपत्ति है, दोनों भाइयों ने कई बार यह कहा था कि वह फ्लैट उस अज्ञात कंपनी ने अजिताभ को दिया है, जिसके लिए वह वहां काम करते हैं, वह उनका अपना नहीं है, वह ढाई बेडरूम का नहीं जैसा अमिताभ ने कहा था पांच बेडरूम का है और सबसे बड़ी बात यह कि उसे अप्रैल, १९८६ में अजिताभ ने खरीदा था और उसकी बाजार की कीमत ६८ से ८५ लाख रुपये है।

यह विस्फोटक दस्तावेज़ राम जेठमलानी ने अपनी स्विटजरलैंड यात्रा में प्राप्त किया था। लेकिन वह इसे अपने साथ नहीं लाये, ताकि कहीं पकड़ न लिये जायें। यह दस्तावेज फैक्सीमिले मशीन पर पहले राजधानी के एक बड़े होटल में आया, वहां से जेठमलानी को दिया गया। सूत्रों के अनुसार होटल के एक कर्मचारी से सरकार को यह पता चल गया और इसीलिए उसके अगले दिन, छपने से पहले ही राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा ले लिया।

इस खबर के छपते ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि इतने गंभीर आरोप को ध्यान में रखते हुए या तो अजिताभ के विरुद्ध या झूठ बोलने के लिए अरुण शौरी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। उसी शाम प्रधानमंत्री ने अजिताभ बच्चन के विरुद्ध आरोपों की जांच के आदेश दे दिये। जांच यदि ईमानदार हुई, तो उसके परिणाम बुरे ही हो सकते हैं—बच्चन-बंधुओं और राजीव गांधी तीनों के लिए। (देखें संलग्न कथा)

एक दिन पहले विद्याचरण शुक्ल ये आरोप लगा चुके थे कि राजीव गांधी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला बनता है। अगले दिन आरिफ मोहम्मद खां ने कहा कि बोफोर्स तोपों के सौदे में करोड़ों रुपये का कमीशन लेनेवाला बिचौलिया और कोई नहीं, स्वयं राजीव गांधी हैं।

ये सारी घटनाएं, १७-१८ जुलाई की थीं। इससे पहले अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां और

आरिफ पर हमले की असलियत

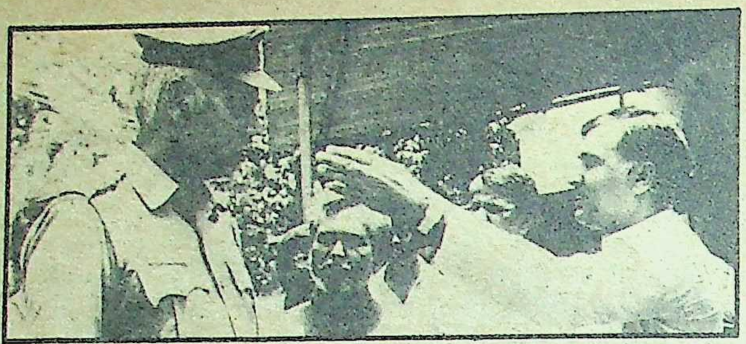

अभी और ज्यादा खतरनाक हमला होना बाकी था। कांग्रेस से निकाले जाने के ४८ घंटे के अन्दर ही किये गये 'प्राणघातक हमले' से आरिफ मोहम्मद खां सुरक्षित बच निकले थे। १७ जुलाई को जुमे के दिन सुनहरी बाग रोड स्थित उनके बंगले पर तीन बार घात लगायी गयी। तीसरी बार आये युवक इंकाइयों व गुंडों की भीड़ ने न केवल घेर कर उन पर हमला कर दिया, बल्कि उन पर गोलियां भी चलायी गयीं। किंतु इन हमलों से वह विचलित नहीं हुए थे और न ही उत्तेजित। आरिफ, उनके अंगरक्षक व घर के मौजूद साथी इन हमलों का भी मुकाबला करने में सक्षम थे। हमलावर खदेड़ दिये गये।

लेकिन, इसके अगले ही दिन, १८ जुलाई की शाम आरिफ पर हुआ हमला और भी खतरनाक था। इस बार हमलावर युवक कांग्रेस के छुटभैये कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द शर्मा तथा राष्ट्रीय महासचिव सुरेश पचौरी थे। इन दोनों युवक कांग्रेसी नेताओं ने राजधानी में एक प्रेस कांफ्रेंस कर आरिफ मोहम्मद खां पर—झूठी नौटंकी रचने, आपराधिक कृत्य करने, तथा अपने ऊपर खुद प्राणघातक हमले का नकली नाटक करवा सस्ती लोकप्रियता व सहानुभूति बटोरने का आरोप लगाया।

घटनाक्रम : शुक्रवार की सुबह आरिफ मोहम्मद खां के मकान के सामने दो लड़के संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लड़के घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर आरिफ के यहां आने-जानेवाली कारों के नंबर एक अखबार पर नोट करने लगे। आरिफ के घर में मिलने तथा बधाई देनेवालों का तांता लगा हुआ था। ऐसे में जब बहुत देर तक ये लड़के संदिग्ध अवस्था में बाहर बैठे रहे, तो घर में मौजूद कुछ व्यक्तियों को उन पर शक हुआ। आरिफ के यहां रहनेवाले एक कर्मचारी का कहना था कि, "पहले तो हमें यह लगा कि ये सी०आई०डी० वाले हैं जो यहां जासूसी कर रहे हैं।" मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद से आरिफ के घर पर गुप्तचर कर्मचारियों द्वारा लगातार निगाह रखे जाने तथा आते-जाते लोगों के नाम व गाड़ियों के नंबर नोट करना कोई नयी बात नहीं है, "लेकिन उन लड़कों की हरकतों से यह संदेह हुआ कि ये सिर्फ जासूसी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और खतरनाक मकसद से यहां बैठे हैं।"—उस कर्मचारी का कहना था। उसके बाद उन दोनों लड़कों को आरिफ के समर्थकों ने जाकर पकड़ा तथा उनके हाथ से वह समाचार पत्र छीन लिया, जिस पर गाड़ियों के नंबर नोट थे। इन दोनों लड़कों को पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन भेज दिया गया।

किंतु, थोड़ी देर बाद वह दोनों लड़के—राजेश मिश्र और निशांक जैन वापस फिर घर के सामने लौट आये। इस बार उनके साथ एक लड़का और था। ये तीनों पुनः घर के फाटक पर चहलकदमी करने लगे। अबकी बार आरिफ के समर्थकों ने इनको पकड़कर अपने घर पर बैठा लिया। जब इन लड़कों को पकड़कर घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो उन्हें छुड़ाने के लिए लगभग तीस लड़कों का एक जत्था वहां पहुंच गया, जिनके तथा आरिफ मोहम्मद के समर्थकों के मध्य जमकर हाथापाई हुई। इनमें दो लड़के तो पकड़ लिये गये, शेष भाग गये। पकड़े गये इन लड़कों की जमकर धुनाई की गयी।

लगभग साढ़े पांच बजे जैसे ही आरिफ मोहम्मद खां अपने घर वापस लौट रहे थे, उनके मकान के बाहर लगभग पांच मिनट पहले पहुंची ५०-६० व्यक्तियों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पहले यह भीड़ आरिफ मोहम्मद खां की कार को फाटक पर ही घेरकर नारे लगाने लगी। कार में आरिफ व उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ दो पत्रकार भी थे। जैसे ही आरिफ कार के बाहर निकले, उन्हें चारों तरफ से दबोच लिया गया। अपने हाथ में लिये काले झंडों व डंडों से आरिफ पर वार शुरू हो गये, किंतु तब तक आरिफ के हथियारबंद सुरक्षाकर्मी उन्हें मुस्तैदी से चारों तरफ से घेरे में सुरक्षित ले चुके थे। घर के बाहर शुरू हुए इस शोर-शराबे को सुनकर कुछ ही क्षणों में अंदर मौजूद आरिफ समर्थकों की भीड़ फाटक पर पहुंच चुकी थी। आरिफ समर्थकों तथा हमलावरों के मध्य जमकर मारपीट हुई। इस बीच जैसे ही आरिफ अपने सुरक्षाकर्मियों से घिरे फाटक के अंदर की तरफ बढ़े एक-के बाद-एक तीन गोलियां चलने की आवाजें आयीं। इससे पहले कि गोली चलानेवाले को पकड़ा जा सके, फाटक के दस फुट आगे पहले से खड़ी एक कार में हमलावर कूदकर घुस गये तथा भाग खड़े हुए।

कुछ ही देर में आरिफ मोहम्मद खां पर हुए हमले की खबर राजधानी में चारों तरफ फैल चुकी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू, सत्यपाल मालिक सहित तमाम नेता आरिफ के घर पहुंच चुके थे। पत्रकारों से घिरे आरिफ का कुर्ता फटा हुआ था तथा उनके उत्तेजित समर्थक इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे थे। वहां पकड़े गये युवक कांग्रेसी कराहते हुए एक कमरे में बंद पड़े थे। आरिफ के समर्थकों ने इनकी अच्छी खासी धुनाई की थी।

आरिफ मोहम्मद खां के ऊपर हमला करनेवालों में पकड़े गये युवक-कांग्रेसियों को पुनः तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। जहां रात को ही आनंद शर्मा तथा सुरेश पचौरी के फोन पहुंचने पर उन्हें छोड़ दिया गया। हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। किंतु अगले दिन आनंद शर्मा तथा सुरेश पचौरी द्वारा जहां एक तरफ आरिफ को गिरफ्तार करने की मांग की गयी, वहीं दूसरी तरफ आरिफ के घर पकड़े गये दो लड़कों के कहने पर पुलिस ने आरिफ तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध गैरकानूनी ढंग से बंधक बनाने तथा मारपीट करने की शिकायतें दर्ज कर ली हैं।

पुलिस द्वारा इस पूरे कांड में की गयी भूमिका के ऊपर आरिफ मोहम्मद खां की टिप्पणी थी, "मैं पुलिस को क्या दोष दूं, वह बेचारी तो वही करेगी जो उसे ऊपर से करने को कहा जायेगा।" किंतु इस पूरे हमला-प्रकरण से उठनेवाले सवालों की तरफ आरिफ लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित करते हैं कि क्या अब राजनीति की यही शैली इन लोगों के पास बाकी बची है? क्या यह गोली व ताकत से मुझे डरा-धमका पायेंगे? वहीं राजधानी में लोग इस बात पर भी आश्चर्यचकित हैं कि आरिफ मोहम्मद खां के आवास के क्षेत्र में जो वी०आई०पी० जोन में आता है, दिन में दो बार, पहले २५-३० तथा दुबारा ५०-६० लोगों का जत्था डेढ़ किलो मीटर दूर, ३ रायसीना रोड से पैदल चलकर हमला करने पहुंचा तथा चप्पे-चप्पे पर खड़ी वायरलैसधारी पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें रोका तक नहीं। जबकि इस क्षेत्र में सदैव धारा १४४ लगी रहती है और सामान्य आदमियों तक पर पुलिस कड़ी निगाह रखती है। बताया जाता है कि ये पकड़े गये युवक मध्य प्रदेश के हैं। आरोप है कि सुरेश पचौरी की शह पर ही इन लड़कों ने आरिफ पर हमला किया था। इस संदर्भ में चर्चा है कि आरिफ पर हुए हमले के असफल हो जाने के बाद आनंद शर्मा तथा सुरेश पचौरी की ऊपर से जमकर खिचाई की गयी। इसके बाद ही फिर नयी रणनीति के तहत इन दोनों नेताओं ने सीधे खुद हमला करने की पहल संवाददाता सम्मेलन बुलाकर की थी।

आरिफ के घर मौजूद एक इंका सांसद का कहना था, "ये लोग (सत्ताधारी लोग) किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं, पर इतनी जल्दी इस स्तर पर उतर आयेंगे, यह आशा नहीं थी।"

—पुनीत टण्डन

विद्याचरण शुक्ल को १५ जुलाई की रात को कांग्रेस से निकाला जा चुका था। उसी दिन ऋषिकेश, हरिद्वार में वी०पी० सिंह, आरिफ तथा सतपाल मलिक ने विशाल जनसभा को पहली बार एक साथ संबोधित किया था। दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में लगभग ५० स्थानों पर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था।

वी०पी० सिंह का पैंतरा: १६ की सुबह आरिफ और सतपाल मलिक दिल्ली लौटे, तो अखबारों में उनके निष्कासन की खबर थी। उन्हें सूचना पिछली रात ही मिल गयी थी। वी०पी० सिंह एक दिन रुक गये थे। साथियों के निष्कासन की सूचना मिलने के बाद उन्होंने मां आनंदमयी के आश्रम में दर्शन किये, फिर जयराम आश्रम में दो घंटे अपने साथियों, समर्थकों के साथ, फिर एकांत में दो घंटे विचार किया, कार से बुलंदशहर से तार से अपना इस्तीफा (या इस्तीफे का प्रस्ताव) राजीव गांधी को भेज दिया।

MINISTER OF STATE IN
M H A

बहुत करीब से बहुत दूर: राजीव गांधी और अरुण नेहरू

१७ जुलाई की घटनाओं का वर्णन ऊपर हो चुका है। किंतु उस दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना दूसरी थी जो लोगों को अगले दिन पता चली। रक्षा राज्यमंत्री और कभी राजीव गांधी के सर्वाधिक प्रिय, अंतरंग और विश्वस्त सहायक-मित्र अरुण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। यह एक सप्ताह में राजीव मंत्रिमंडल से दूसरा इस्तीफा था। तीन दिन पहले पर्यटन मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पदत्याग कर चुके थे।

वी०पी०सिंह

राजा अब शर्मीले विद्रोही नहीं बने रह सकते। १९७७ में जो स्थिति जे०पी० की थी, वह स्थिति आज वी०पी० की है।

१७, १८ और १९ को सब ओर उत्सुकता बनी रही कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के त्यागपत्र के प्रस्ताव पर राजीव गांधी क्या रुख अपनायेंगे। अपने पत्र में राजा साहब ने भारी-भारी शब्दों में नेहरू, आरिफ, शुक्ल के निष्कासन की आलोचना की थी, इस कदम को 'सामंती' तथा अलोकतांत्रिक कहा था और बिना नाम लिये राजीव गांधी को पार्टी का बिना चुना हुआ, नामजद नेता कहा था।

यदि वी०पी० सिंह अपने साथियों के निष्कासन के बाद उसका ऐसा कड़ा जवाब देने में ४८ घंटे की देर कर देते, तो 'राजनीतिक रूप से खतम हो जाते', एक सांसद की टिप्पणी थी। किंतु राजा साहब ने वह आक्रामक, लेकिन चतुर-पत्र लिखकर सिद्ध कर दिया कि वह सचमुच नेता हैं।

लेकिन उस पर राजीव गांधी की जो प्रतिक्रिया हुई उससे उन्होंने अपना कद और छोटा कर लिया है। लोगों की अपेक्षा थी कि इतने कठोर पत्र के बाद कोई भी स्वाभिमानी नेता इस्तीफे को स्वीकार कर लेता। किंतु १७ की शाम को पत्रकारों को कांग्रेस महासचिव ज़ी०के० मूपनार ने बताया कि वी०पी० सिंह की बातें और कार्य पार्टी-विरोधी नहीं, पार्टी के सिद्धांतों के अनुकूल हैं। स्वयं प्रधानमंत्री की टिप्पणी थी, "इस्तीफा सशर्त है।"

आरिफ मोहम्मद खान

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बोफोर्स तोपों के सौदे में करोड़ों रुपए का कमीशन लेनेवाला बिचौलिया और कोई नहीं, स्वयं राजीव गांधी हैं।

यही नहीं, १८ जुलाई को अजिताभ पर इंडियन एकसप्रेस के आरोप के संबंध में वी०पी० सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसी शाम उन आरोपों की जांच की घोषणा हो गयी। इन घटनाओं से पिछली इन आशंकाओं को बल मिला कि नेहरू, आरिफ, शुक्ल को निकालते समय उनके नेता वी०पी० सिंह को छोड़ने के पीछे कांग्रेस आलाकमान की यह नीति थी कि राजा साहब को अन्य तीनों से अलग-थलग किया जाये और फिर फोड़ने के प्रयास किये जायें। लोगों को लगा कि ये घटनाएं इसी योजना की कड़ी हैं।

पार्टी हाईकमान से कोई उत्तर न आने के कारण वी०पी० सिंह भी अपनी स्थिति और योजना स्पष्ट नहीं कर रहे थे। उनका दो दिन एक ही उत्तर रहा, 'पहले मैं यह तो जान लूं कि मैं पार्टी में हूं या नहीं।' यह उत्तर उन्हें १९ जुलाई को मिल गया। उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था।

उनके निष्कासन के विरोध में कांग्रेसी सांसद सत्यपाल मलिक, आनंद सिंह, भानुप्रताप सिंह, दीप नारायण महंत (सभी उ०प्र० के) ने इस्तीफा दे दिया। अभी उनके इस्तीफे हाईकमान के पास पहुंचे भी न होंगे कि खबर सुनकर ही हाईकमान ने इन सभी को पार्टी से निष्कासित किये जाने की घोषणा कर दी। भूतपूर्व कांग्रेस महासचिव रामधन शुरू से इन लोगों के साथ हाईकमान के विरुद्ध वक्तव्य दे रहे थे, किंतु उनका निष्कासन बाद में हुआ।

लेकिन उन अभूतपूर्व सनसनी भरे दिनों में राजनीतिक गतिविधियां कई अन्य स्तरों पर भी हो रही थीं।

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध असंतुष्टों ने लगभग खुला विद्रोह कर दिया था। उ०प्र० के २३ विधायक एक

संयुक्त पत्र में नेहरू, आरिफ, शुक्ल के निष्कासन का विरोध कर चुके थे। अन्य ६० विधायकों द्वारा प्रदेश में नेतृत्व-परिवर्तन के लिए राजीव गांधी को लिखे पत्र की चर्चाएं चल रही थीं। १७-१८ जुलाई को तो लगा कि वीर बहादुर सिंह का हटाया जाना अटल है। समाचार छप गये कि रविवार तक उनका इस्तीफा हो जायेगा और लोकपति त्रिपाठी नये मुख्यमंत्री होंगे।

मुख्यमंत्री सहित दर्जनों असंतुष्ट विधायक तथा मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार—लोकपति, संजय सिंह तथा सुनील शास्त्री दिल्ली में डेरा डाले पड़े थे। शनिवार को अचानक स्पष्ट संकेत मिले कि वीर बहादुर को एक महीने का समय और मिल गया है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वी०पी० सिंह के खतरे को प्रदेश में केवल वही झेल सकते हैं। शनिवार को वह लखनऊ लौटे तो उनका रुख ही दूसरा था। वह 'सड़क-छाप खबरें लिखनेवाले सड़कछाप पत्रकारों' और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखनेवाले मंत्रियों दोनों पर समान रूप से गरजे। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन की अनुमति मिल गयी थी। फिर उन्होंने जाफर अली नकवी और सुरेन्द्र सिंह को मंत्रिमंडल से 'बरखास्त' कर दिया, जबकि दोनों का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया।

उधर महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल, शरद पवार और दोनों के समर्थकों ने मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के विरुद्ध सार्वजनिक युद्ध छेड़ दिया था। पाटिल यों तो राजस्थान के राज्यपाल हैं, किंतु चव्हाण के खिलाफ उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ से ही खुली राजनीतिक मुहिम चलाये हुए हैं। उन्होंने ३१ अगस्त तक चव्हाण को हटाने के लिए हाईकमान को अल्टीमेटम भी दे दिया था। वह अपने शिष्य, उत्तराधिकारी तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल-निलंगेकर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उधर शरद पवार और उनके ५० से ऊपर समर्थक भी हाईकमान पर जोर डाल रहे थे कि पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाये।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक एक ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद नित्यानंद मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री-विरोधी विधायक-सांसद दूसरी ओर हाईकमान से मिलकर जोर आजमाइश कर रहे थे।

इन तीनों प्रदेशों के असंतुष्टों का कहना है कि यदि वर्तमान मुख्यमंत्री थोड़ा समय और चल गये, तो प्रदेशों से कांग्रेस का हरियाणा की तरह पत्ता साफ होने में कोई कसर नहीं बचेगी। १५-१६ जुलाई तक तो यह लग रहा था कि इन तीन-चार राज्यों में एक साथ नेतृत्व-परिवर्तन होगा। विकल्पों की तलाश और चर्चाएं जोरों पर थीं। लग रहा था, सबसे पहले बारी उत्तर प्रदेश की आयेगी, किंतु तीन बातों ने सारा मामला ठंडा कर दिया। पहला, वर्तमान मुख्यमंत्रियों का सही विकल्प नहीं मिल रहा था। दूसरा, कम-से-कम वीर बहादुर तथा पटनायक की इस 'धमकी' की खबर हाईकमान तक पहुंच गयी थी कि यदि उन्हें हटाया गया, तो वे अपने-अपने प्रदेशों में जगन्नाथ मिश्र बन जायेंगे। इस अप्रिय संभावना और जुलाई के दूसरे पक्ष में हुए एक-के-बाद दूसरे राजनीतिक धमाकों ने हाईकमान को परिवर्तन से विमुख कर दिया। राजीव गांधी को यह बात समझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी माखनलाल फोतेदार ने जो इन दिनों प्रधानमंत्री के शायद एकमात्र और मुख्य राजनीतिक सलाहकार हैं।

विद्याचरण शुक्ल

विद्याचरण शुक्ल ये आरोप लगा चुके थे कि राजीव गांधी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला बनता है।

गतिविधियों का तीसरा स्तर था, पार्टी नेतृत्व। हर नये दिन के साथ बढ़ते जाते इस अभूतपूर्व संकट के हर नये मोड़ से निपटने के लिए लगातार प्रधानमंत्री निवास पर बैठकें हो रही थीं। उबरने के हर संभव उपायों पर विचार और अमल किया जा रहा था। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को विचार-विमर्श के लिए चुना था, वे थे—फोतेदार, पी० शिवशंकर, कांग्रेस महासचिव नवल किशोर शर्मा, जिन पर उनका विश्वास पिछले दिनों काफी बढ़ा है और अर्जुन सिंह, जिनके बारे में मान लिया गया था कि उनके राजनीतिक उत्कर्ष का चक्र संचार मंत्री के पद पर आकर ठहर गया है।

उन दिनों अर्जुन सिंह का लगभग पूरा समय प्रधानमंत्री निवास में बीत रहा था। नित्य बदलती परिस्थिति से निपटने की रणनीति के वह एक प्रमुख अंग बन गये थे। बावजूद इसके कि संकट की इस घड़ी में अर्जुन सिंह के प्रतिद्वंद्वी मोतीलाल वोरा को भी उनसे हिसाब बराबर करने का अवसर मिला और उसे भुनाने में वह चूके नहीं। 'माया' को प्राप्त सुपुष्ट सूचना के अनुसार अपेक्षाकृत कम विश्वसनीयता के एक अंग्रेजी साप्ताहिक में चुरहट लाटरी कांड के संबंध में अर्जुन सिंह को लपेटती खबर स्वयं 'सज्जन' मुख्यमंत्री वोरा ने उसके संपादक को सारे दस्तावाजों सहित दी थी।

लेकिन संचार मंत्री का विख्यात राजनीतिक कौशल तथा मौन कूटनीति का अनुभव उनके अतीत या संदिग्ध गतिविधियों की अपेक्षा उस समय अधिक प्रासंगिक था। राजीव गांधी के सलाहकारों में नरसिंह राव भी थे, यद्यपि स्वयं उनकी निष्ठा तथा मंतव्य के बारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं।

उस सप्ताह की कई रोचक बातों में एक के केन्द्र थे, अपने पं० कमलापति त्रिपाठी जो शायद चर्चा के बाहर रह ही नहीं सकते। एक ओर कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें बुलाकर आधे घंटे तक पार्टी के पुनर्गठन के संबंध में विचार-विमर्श कर रहे थे, दूसरी ओर 'बाबू' निष्कासित विद्याचरण शुक्ल को अपने घर पर लंबा भोजन करा रहे थे, आरिफ मोहम्मद खान को फोन पर और साक्षात अनुभवजन्य सीखें दे रहे थे। जिस दिन प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने घर बुलाया, उसी शाम अनन्य राजीव-भक्त और कमलापति-द्रोही काशी के सांसद रत्नाकर पांडे ने बयान देकर आरोप लगाया कि इस सारी समस्या के पीछे उनका (पण्डित जी) दिमाग है।

अरुण नेहरू

अरुण नेहरू के बाण छूट रहे थे "हमला करनेवालों को दोष देना बेकार है। दोष उनको आदेश देनेवालों का है।"

राजीव क्या करेंगे : पार्टी के सांसदों, नेताओं के लिए राजीव गांधी अचानक सुलभ हो गये थे। अकेले या सामूहिक रूप से मिलनेवाले सांसदों से वह पूछ रहे थे 'खुल कर बताओ, क्या करना चाहिए।' केन्द्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल की चर्चाओं के चलते दर्जनों महत्वाकांक्षी सांसदों को सूक्ष्म संकेत दिये जा रहे थे कि अधीर न हों, इस समय डटकर काम करें, उनका 'कुछ' होगा।

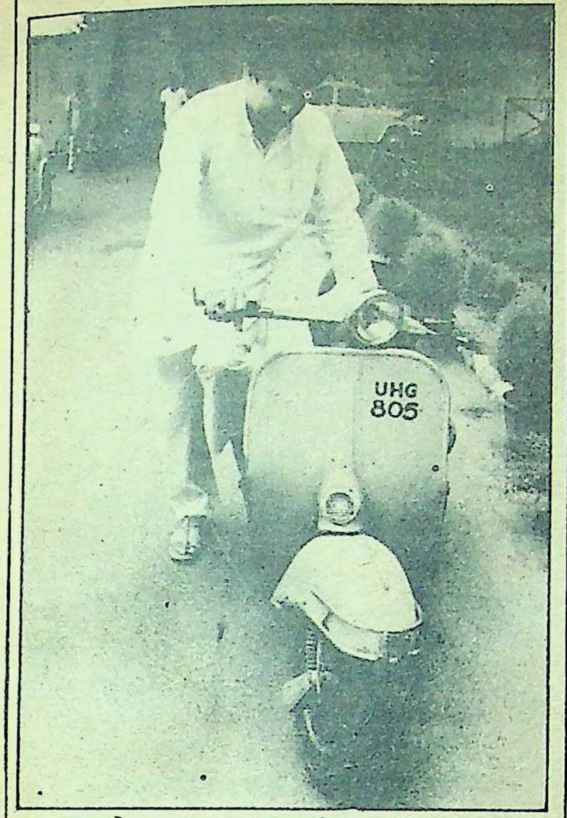
पदत्याग के बाद: जफर अली नकवी

पार्टी क्षेत्रों के विचार-विमर्श का उन दिनों एक प्रमुख मुद्दा था, क्या राजीव गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किसी योग्य व्यक्ति को बिठाना चाहिए? उनके सलाहकारमंडल में इस पर मतांतर था।

भक्तों की राय थी कि संकट की इस वेला में पार्टी की कमान राजीव गांधी के ही हाथों में रहनी चाहिए। किसी दूसरे को सत्ता के इस समान्तर शिखर पर बिठाना बहुत सुरक्षित नहीं। किंतु उनके दो अराजनीतिक मित्र-सलाहकार कुछ और राय दे रहे थे। टाइम्स आफ इंडिया के वयोवृद्ध संपादक और देश के प्रमुख बुद्धिजीवी गिरिलाल जैन बार-बार अपने लेखों में जोर दे रहे थे कि राजीव गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व किसी और को सौंपना चाहिए जो उनका भार कम कर सके और जिससे पार्टी में लोकतंत्रीकरण तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण की वर्षों से रुकी हुई परंपरा आरंभ हो। दि टेलीग्राफ के युवा, प्रतिभाशाली संपादक एम०जे० अकबर ने पिछले कुछ महीनों में राजीव गांधी का ऐसा खुला और कभी नंगा समर्थन किया कि उनकी अपनी विश्वसनीयता और साख स्थाई रूप से प्रभावित हो गयी। वही अकबर अपने संपादकीय में सलाह दे रहे थे कि राजीव गांधी को नारायण दत्त तिवारी को पार्टी अध्यक्ष बना देना चाहिए, मंत्रिमंडल और संगठन में आमूल परिवर्तन करके ईमानदार तथा स्वच्छ छवि के लोगों को लाना चाहिए तथा वीर बहादुर, दुबे और पटनायक जैसे मुख्यमंत्रियों की तत्काल छुट्टी कर देनी चाहिए।

पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आर० वेंकटरमण की राष्ट्रपति चुनाव में भरपूर बहुमत से जीत के बावजूद कांग्रेस में माहौल प्रसन्नता और उत्साह का नहीं, आशंका और अनिश्चितता का था। हरियाणा चुनाव के बाद से ही सब यह तय मान रहे थे कि अब केन्द्रीय मंत्रिमंडल, पार्टी और प्रदेश इकाइयों तथा सरकारों में व्यापक परिवर्तन होंगे, हर स्तर पर कांग्रेस को निखारा, संवारा जायेगा। किंतु, ये परिवर्तन कैसे, कब और किस क्रम में होगें, यह कोई नहीं जानता था। वरिष्ठ मंत्री पत्रकारों से पूछ रहे थे, "क्या होने वाला है?"

प्रधानमंत्री के एक करीबी सहायक-सलाहकार 'माया' से कह रहे थे, "मैं इस दृढ़ मत का हूं कि परिवर्तनों का पूरा 'पैकेज' होना चाहिए, अब धीरे-धीरे, एक-एक करके कदम उठाने का समय नहीं है। संगठन और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो या कुछ नये, बड़े कदमों की घोषणा, अब सब कुछ नेतृत्व की निर्णय-प्रक्रिया में एक साथ होना चाहिए।" लेकिन

111156

साक्षात्कार/तारिक अनवर

अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल

वी०पी० सिह कहां तक ईमानदार हैं, समय बतायेगा

माया: हाल के निष्कासनों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

तारिक: यह कोई अच्छी बात तो नहीं है, पर मजबूरन कदम उठाना पड़ता है।

माया: वी०पी०सिह का इस्तीफा न स्वीकार करने के पीछे क्या नीति है?

तारिक: वी०पी०सिह ने इस्तीफा दिया ही नहीं है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री पर बात छोड़ दी है, चिट्ठी लिखकर और प्रधानमंत्री तो उन्हें निकालना नहीं चाहते। हां अगर वी०पी०सिह महसूस करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना है, तो साफतौर पर लिखकर देना चाहिए था। फिर राज्यसभा से इस्तीफे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती।

माया: पिछले दिनों विपक्ष और प्रेस ने जो भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री और उनके मित्रों पर लगाये हैं; क्या उन पर खुलकर जांच होनी चाहिए।

तारिक: जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, उन्हें सच्चाई का रूप कैसे दिया जा सकता है। आरोप लगानेवालों ने आज तक कोई प्रमाण तो दिया नहीं है।

माया: आज ही 'इंडियन एक्सप्रेस' में अजिताभ बच्चन के स्विटजरलैंड स्थित मकान का एक दस्तावेज छपा है?

तारिक: अजिताभ बच्चन पर आरोप का सरकार से क्या लेना-देना। फिर अखबारों में कुछ चीजें गलत भी छप जाती है। मसलन भूरेलाल का फेयरफैक्स को लिखा पत्र। इसका मतलब यह तो

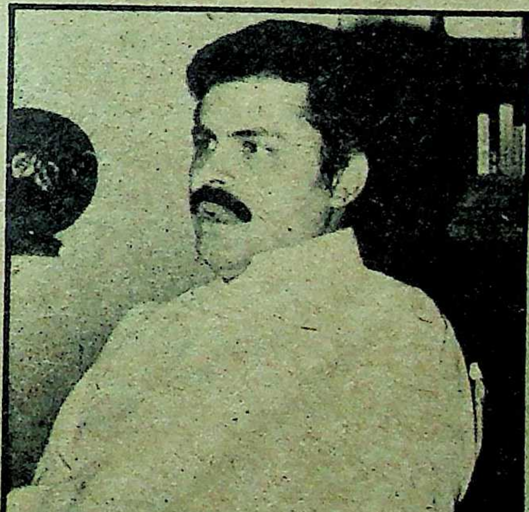

नहीं की सब सच मान लें।

माया: आपकी पार्टी में आन्तरिक विद्रोह के स्वर उभरने लगे हैं। उससे कैसे निपटेंगे?

तारिक: ऐसी कोई फीलिंग (भावना) नहीं है। हाल में राष्ट्रपति के चुनाव में हमें अपने दल से ज्यादा मत मिले। यह हमारी एकता का प्रमाण है।

माया: वी०पी०सिह ने जनजीवन में, चुनावों में और औद्योगिक प्रबंधों में सुधार के जो मुद्दे उठाये है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं?

तारिक: वी०पी०सिह कहां तक ईमानदार हैं, समय बतायेगा। वह जहां आज पहुंचे हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने वही सीढ़ियां चढ़ी हैं जो हर कांग्रेसी चढ़ता है। फिर यह अचानक नैतिकता की बातें किसे मूर्ख बनाने के लिये हैं?

माया: पर लोग तो ऐसा नहीं मानते। आपके दल और नेता के वक्तव्यों की विश्वसनीयता में कमी आयी है, यह आप भी मानेंगे?

तारिक: अगर बच्चा ही बाप के खिलाफ अचानक बोलने लगे, तो लोग यकीन करेंगे ही। राजीव गांधी ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी—पहली बार उन्होंने ही इससे लड़ने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य यह है कि उनकी ही नीतियों पर अमल करके कुछ लोग उन्हें ही भ्रष्टाचारी सिद्ध करना चाहते हैं। दरअसल लड़ाई मूल्यों की नहीं सत्ता के केन्द्र में रहने की है।

माया: यह लड़ाई कहीं इसलिए तो नहीं कि आपके दल कांग्रेस-इ में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है?

तारिक: हम शीघ्र दल के चुनाव करवाने जा रहे हैं। पहले भी चुनाव टालने की वजह इस में होने वाली संभावित गड़बड़ियों से बचना था, न कि लोकतांत्रिक मूल्यों से मुंह मोड़ना। ■

अगले ही क्षण वह कह रहे थे, "मगर मैं प्रधानमंत्री से परसों से मिला नहीं हूं, मिलूं तो यह स्पष्ट कहूंगा।"

रविवार को चर्चा गर्म थी कि अमिताभ बच्चन के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने कैप्टेन सतीश शर्मा, माधवराव सिंधिया, जगदीश टाइटलर आदि से भी इस्तीफे ले लिये हैं। सभी पर अलग-अलग आरोप हैं। शाम की सूचना थी कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से इस्तीफे ले लिये गये हैं। हड़कम्प भरे माहौल में जितने लोग, उतनी बातें।

राष्ट्रपति जैल सिंह अपने विदायी दौरों पर थे। उनके कार्यकाल के चंद दिन बाकी थे। लेकिन कांग्रेस क्षेत्रों में भय अब भी बना हुआ था, 'कहीं चलते-चलते ज्ञानीजी कुछ अनर्थ तो नहीं कर जायेंगे।' लोग उनके लौटने की राह देख रहे थे। जार्ज फर्नांडीस, राम जेठमलानी और पत्रकार राजेन्द्र पुरी ज्ञानीजी को ताजे पत्र लिखकर नये आरोपों और तथ्यों की रोशनी में राजीव गांधी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रहे थे।

अजिताभ के स्विस फ्लैट के स्वामित्व की असलियत के रहस्योद्घाटन और एक अरुण सिंह के इस्तीफे ने इन शंकाओं को पुष्ट किया था कि ये मामले और अधिक खुले तो कहीं राजीव गांधी स्वयं भ्रष्टाचार में न फंस जायें। यद्यपि अरुण सिंह के इस्तीफे के कारणों के बारे में वह चुप थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस्तीफे के दो कारण थे। एक तो कई विवादास्पद रक्षा सौदों में हुई अनियमितताओं का उन्हें पता चल गया था और रक्षामंत्री होने के नाते अगले संसद के सत्र में वह सरकार का पक्ष जोर से रख पाने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। दूसरे उन्हें इस बात का बहुत मलाल था कि राजीव गांधी ने जानबूझकर कई रक्षा संबंधी तथ्यों को उनसे छिपाया था। वह इससे भी रुष्ट थे कि बोफोर्स कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने तथा सरकार को तथ्यों का पता लगाने में सहयोग करने के लिए तैयार था, किंतु भारत सरकार ने इसके लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। अरुण सिंह ने संसद में कहा था कि कोई दलाल नहीं है, लेकिन अब वह यह कहने की स्थिति में नहीं थे। इसके अतिरिक्त बोफोर्स के मामले में प्रधानमंत्री ने अपने एक और दोस्त को सक्रिय कर दिया था जो अरुण सिंह को बरदाश्त नहीं था। वैसे सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा फरवरी में ही दे दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया।

एक ही सप्ताह में इस्तीफा देनेवाले भीतर-भीतर विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू आदि से मिले हुए नहीं हैं। कम-से-कम अभी तक। मुफ्ती के स्वर से लगता है, संभव है, वह देर-सबेर इन लोगों के साथ आ जायें। किंतु, अरुण सिंह के स्वभाव और अतीत को देखते हुए उनका राजीव गांधी को अपदस्थ करने की योजना में शामिल होना कठिन लगता है (हां, अब असंतुष्टों का सीधा, घोषित लक्ष्य राजीव गांधी को हटाना है)। कभी देश में

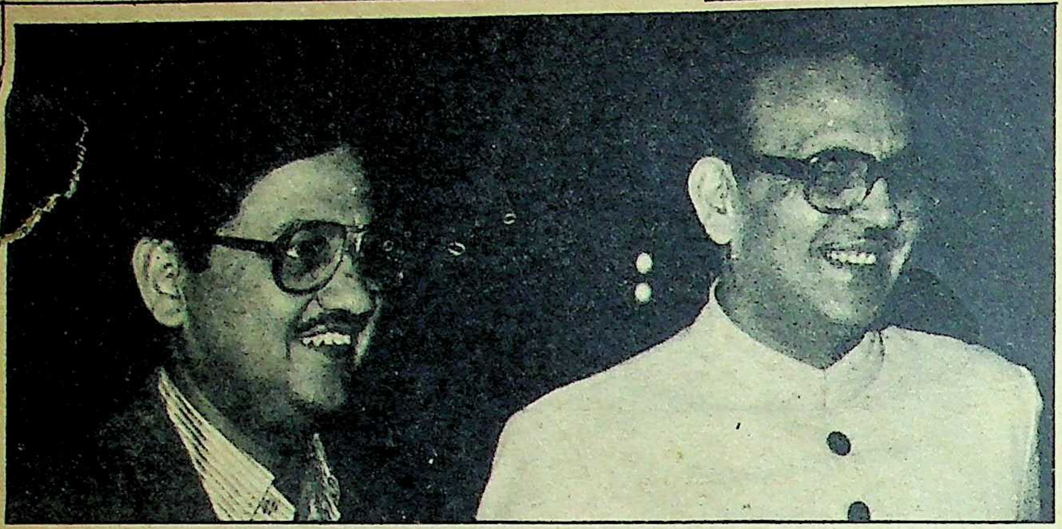

मैंने इस्तीफा दिया : सुनील शास्त्री राजा के साथ

साक्षात्कार/आनंद शर्मा

युवा कांग्रेस-इ अध्यक्ष

संदेह दूर होंगे

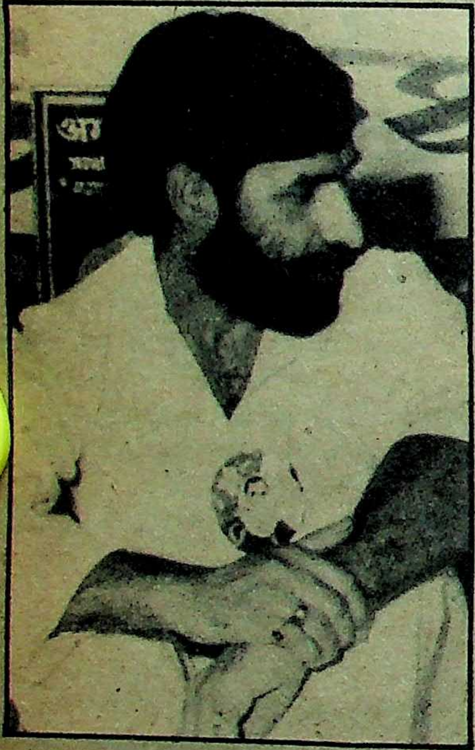

माया : आरिफ मोहम्मद खान और दूसरे इंका सांसदों को पार्टी से निकालने पर आप क्या महसूस करते हैं?

शर्मा : कुछ लोग देश में शंकाएं और भ्रम पैदा करने की कोशिश में जुटे थे। उनकी इन गतिविधियों से इंका विरोधियों की चरित्रहननवाली मुहिम को बल मिल रहा था। इसलिए ऐसा करना पड़ा। आखिर दल का अनुशासन भी कोई चीज है।

माया : अनुशासन लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके तो नहीं कायम किया जाता।

शर्मा : यह दुर्भाग्यशाली स्थिति थी कि हमें पहले दल के चुनाव टालने पड़े। दरअसल, दल की सदस्यता और उसकी विश्वसनीयता के मुद्दों की जांच करवाने में इतना समय लग गया। अब अगले साल के शुरू में ही दल में चुनाव कराये जाएंगे।

माया : यह चुनाव हाल में पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष का परिणाम तो नहीं?

शर्मा : चुनाव कराने का फैसला पहले हीं किया गया था।

माया : फेयरफैक्स से लेकर आज तक उजागर तमाम घोटालों में प्रधानमंत्री और उनकी मित्र मंडली के क्रियाकलापों की पूरी जांच करवाकर क्या नीर-क्षीर विवेक का परिचय दिया जायेगा?

शर्मा : प्रधानमंत्री का आचरण किसी भी शक की सीमा के बाहर है। हां, जांच की जा रही है। सामान्य से ज्यादा तीव्र गति से जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन सरकार से बोफोर्स के मामले में प्राप्त रपट को दल के नेताओं के सामने रखा है और न्यायिक या संसदीय जांच की पेशकश की है।

माया : रामराज्य में धोबी के आरोप की कहानी आपने सुनी होगी?

शर्मा : इन बातों से आज के जमाने में राज्य नहीं चला करते। अगर कुछ लोगों ने आरोप लगा दिये और कुछ ने छाप दिये, तो सरकार काम करना बंद करके क्या सिर्फ जांच ही कराती रहे। हां, जहां जरूरी है जांच की जा रही है। दोषी व्यक्ति को, वह चाहे कोई हो, सजा जरूर मिलेगी।

माया : पर जनता कुछ और सोच रही है। उसका विश्वास जीतने के लिए आप क्या करेंगे?

शर्मा : हम जनता के बीच जाकर हकीकत बतायेंगे।

माया : अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के क्या परिणाम होंगे?

शर्मा : इससे अमिताभ ओर उनकी भूमिका को लेकर पैदा किये जा रहे संदेह दूर होंगे।

माया : मात्र इस्तीफे से ही?

शर्मा : बाकी काम जांच पूरा करेगा। ■

नंबर दो कहे जानेवाले अरुण सिंह को पत्नियों के मनमुटाव के चलते जब राजीव गांधी ने राजनीतिक रूप से पंगु बनाकर रक्षा मंत्रालय में छोड़ दिया था, तो कपूरथला राजपरिवार के इस सदस्य और प्रधानमंत्री के दून-स्कूल-आक्सफोर्ड सखा ने चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कोई गुपचुप राजनीति नहीं की, गुटबाजी में शामिल नहीं हुए, मन लगा कर अपना काम करते रहे। इतना कि आज उच्चतम सेनाधिकारी उन्हें अब तक का सर्वोत्तम रक्षामंत्री मानते हैं। अरुण सिंह अब राजीव-हटाओ अभियान के अंग नहीं बनेंगे, यह तय है। लेकिन यह भी तय है कि उनके त्यागपत्र ने राजीव गांधी की व्यक्तिगत छवि को गहरी क्षति पहुंचाई है, वह अपने-आप में किसी राजनीतिक चाल की चोट से कम नहीं है।

संभावनाए : कांग्रेस की राजनीति अब तलवार की धार की तरह साफ और सीधी है। महीनों की दुविधा और शंकाओं के बाद कई बातें अब निश्चित हो गयी हैं :

- कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजीव से खुला युद्ध शुरू हो गया है,
- कि वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान तथा विद्याचरण शुक्ल एक लंबी और अंतिम लड़ाई के लिए कटिबद्ध हैं, उनके कदम अब वापस नहीं हो सकते,
- कि लड़ाई अब संसद की वातानुकूलित भव्यता में नहीं, गर्म सड़कों और धूलभरे गलियों-मैदानों में होगी,
- कि राजीव गांधी अकेले पड़ते जा रहे हैं। ढाई वर्ष के शासन काल में उनके सबसे विश्वस्त और अंतरंग सहायक-सलाहकार-मित्र-मंत्री उन्हें न केवल छोड़ चुके हैं, बल्कि अब उन्हें सीधी लड़ाई के लिए ललकार रहे हैं। बचे थे, अमिताभ बच्चन और कैप्टेन सतीश शर्मा। तो अमिताभ से तो विवश होकर राजीव गांधी को इस्तीफा मांगना पड़ा, सतीश शर्मा पहले ही शिखर राजनीति के हाशिए पर आ गये थे।
- कि यह बात गांव-कस्बों के निवासियों तक में घर कर गयी है कि राजीव गांधी बोफोर्स तथा अन्य विदेशी सौदों में स्वयं व्यक्तिगत रूप से फंसे हैं,
- कि बच्चन भाइयों का विदेशों में जमा धन दरअसल राजीव गांधी का है,
- कि राजीव सोनिया गांधी से आवश्यकता से अधिक प्रभावित हैं और सोनिया की भारत के प्रति निष्ठा न अटल है, न असंदिग्ध।
- कि लोग और असंतुष्ट कांग्रेसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को राजीव गांधी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं और मांडा के राजा का यह रूप हर रोज उभर रहा है।
- कि जो सांसद, नेता अभी राजीव गांधी के साथ हैं, वह मन से नहीं, मजबूरी से हैं। भीतर-भीतर सब यह महसूस करते और अकेले में मानते हैं कि भारत और कांग्रेस को चलाना राजीव गांधी के वश का नहीं है।

वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू गुट का दावा है कि वह इस स्थिति में हैं कि उ०प्र० में वीर बहादुर की सरकार गिरा दें। नेहरू के एक करीबी सूत्र का कहना था कि हमारे पास विधायक, सांसद और भी हैं, लेकिन उन्हें हम समय पर बाहर लायेंगे, "एकाध राज्य सरकार गिराने जैसा छोटा-मोटा लाभ हम नहीं चाहते। हम बड़े दांव की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम धैर्यपूर्वक काम करने और इंतजार करने के लिए तैयार हैं।"

निष्कासित नेताओं और विपक्ष में सहयोग की संभावनाओं पर विचार आरंभ हो गया है। चन्द्रशेखर के घर एक रात्रिभोज पर प्रमुख रूप से आमंत्रित थे, बहुगुणा और आरिफ मोहम्मद खान। विद्रोहियों की योजना पहले उ०प्र० पर ध्यान केंद्रित करने की है। एक तो तीनों मुख्य सूत्रधार वहीं के हैं, वहीं तीनों के समर्थक सबसे अधिक संख्या में हैं। दूसरे, कांग्रेस के लिए उ०प्र० संसदीय शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। उ०प्र० हारने का मतलब आधा देश घटना होगा।

राजीव गांधी अपने एक प्रारंभिक निर्णय की बुद्धिमत्ता पर आजकल जरूर अपने को शाबासी दे रहे होंगे। यदि दलबदल विधेयक आज न होता, तो संसद में स्थिति दूसरी ही होती। इस समय ४०० का प्रचंड संसदीय बहुमत राजीव गांधी के संदर्भ में महत्वहीन हो गया है। ढाई वर्ष पहले देवदूत-सा धवल, गरिमामय राजकुमार आज आरोप-मलिन, घायल और असत्यभाषी दिखने लगा है। उसके मुक़ाबले अपनी प्रतिष्ठापित ईमानदारी से और सज्जित ताजी-ताजी शहीदाना आभा से मंडित विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता की निगाह में चढ़ गये हैं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के अधपके राजनीति दर्शन में लोगों को जवाहर लाल नेहरू की गहराई या इंदिरा गांधी का राजनीतिक यथार्थवाद भले ही नजर न आता हो, लेकिन अब यह लगने लगा है कि यदि यही माहौल रहा तो राजीव गांधी के कच्चेपन से बचने के लिए लोग तो राजा साहब को सिर-आंखों पर चढ़ा ही लेंगे। अपने असमय राजनीतिक अवसान से बचने के लिए कांग्रेसी भी उन्हें नेता मानने में क्षण भर की देरी नहीं करेंगे। बस उन्हें सही समय का तथा चीजों के और पकने का इंतजार है।

अब यदि राजीव गांधी एकदम सोने से दमकता मंत्रिमंडल बना लें, कांग्रेस संगठन को निष्ठावान, परिश्रमी, अनुभवी नेताओं से भर दें, राज्यों में बेहतर मुख्यमंत्री ले आयें, तो भी पार्टी के लोग मानने लगे हैं कि बोफोर्स से, अजिताभ-अमिताभ के घोटालों से निकल नहीं पायेंगे। लेकिन अनवरा तैमूर, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, दरबारा सिंह, उमाशंकर दीक्षित, कमलापति त्रिपाठी, जाफर शरीफ जैसे जिन चुके हुए नेताओं को पुनर्जीवित करके पार्टी पुनर्गठन के दिशा-संकेत राजीव गांधी दे रहे हैं, उससे नहीं लगता कि अस्तित्व की इस लड़ाई में भी वह पुराने घाघों 'सत्ता के दलालों' को पूरी तरह छोड़कर कांग्रेस को एकदम नयी दिशा, नया रूप देकर एक सर्वथा नयी शुरुआत करने का साहसिक कदम उठा सकते हैं। अशुभ संकेत तो ये हैं कि इस समय ठीक इमरजेंसी के पहले जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव गोपी अरोड़ा सांसदों की जासूसी में लगे हैं, एच०के०एल० भगत और टाइटलर का काम हर दिन भीड़ जुटा कर राजीव गांधी के निवास पर जिंदाबाद के नारे लगवाना हो गया है। हरिकृष्ण शास्त्री, रमेश भंडारी और कुमार मंगलम सांसदों को पटाते घूमते रहे हैं। दूसरी ओर वी०पी० सिंह जननायक बने हुए हैं। उनके यहां स्वेच्छा से भीड़ उमड़ रही है। ऐसी स्थिति में राजा अब शर्मीले विद्रोही नहीं बने रह सकते। १९७७ में जो स्थिति जे०पी० की थी, वह स्थिति आज वी०पी० की है।

छाया: मनमोहन शर्मा सुनील सक्सेना

—राहुल देव

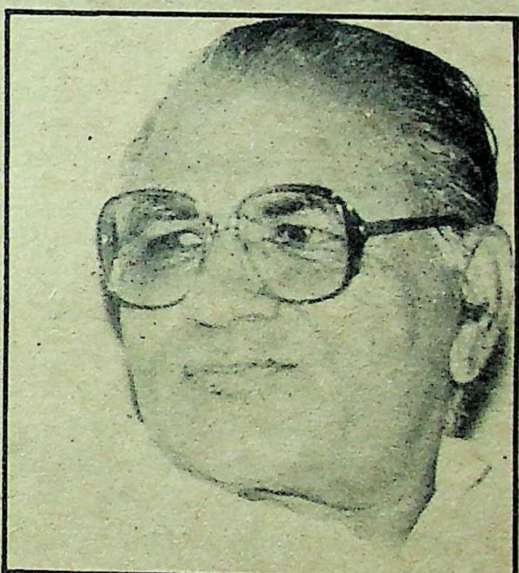

माया : आपने अमिताभ बच्चन के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि 'अगर वह (अमिताभ) पहले इस्तीफा दे देते, तो पार्टी की छवि बिगाड़नेवालों को ऐसा करने का मौका न मिलता', इसका क्या मतलब है?

जोशी : इसका मतलब बहुत साफ-सीधा है। वह यह कि अमिताभ बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। उनका क्षेत्र फिल्म जगत है, राजनीति नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि कभी एक बात बोलने से और कभी दूसरी बात बोलने से ऐसी धारणा पैदा हो गयी है कि जैसे वह कोई गुनहगार हों। बेहतर होता कि वह पहले हट जाते, तो कनफ्लिक्ट (मुठभेड़) में नहीं आते। कनफ्लिक्ट शुरू होते ही हट जाना चाहिए था।

ज्ञानीजी का राजीव को आखिरी सबक

देश दम साधे बैठा था। विपक्षी और असंतुष्ट कांग्रेसी नेता उत्साहित थे और वफादारों के खेमे में हड़कंप मचा था। पता नहीं ज्ञानीजी क्या कर बैठें। राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहने में कुल जमा चार दिन बचे थे और वह विभिन्न राज्यों के विदाई समारोहों में शेरोशायरी करने में मशगूल थे, लेकिन बीच-बीच में जो पटाखे छोड़ रहे थे, उससे वफादारों की धुकधुकी बढ़ रही थी। अब ज्ञानीजी का कोई भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि अंतिम दिनों में उन्होंने जो रंग बदला था, उसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। ज्ञानीजी वही हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा था, अगर अपनी नेता मुझे झाड़ू लगाने के लिए भी कहे, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब वह राजीव गांधी से गिन-गिन कर के हिसाब चुकता करने के मूड में हो गये थे। कारण था—ज्ञानीजी की उपेक्षा। राजीव गांधी के खिलाफ भड़की आग में पहली चिनगारी ज्ञानीजी के खत ने ही छोड़ी थी।

उस समय बहुत तेजी से यह अफवाह उड़ी थी कि अब ज्ञानीजी प्रधानमंत्री को बर्खास्त करेंगे। ज्ञानीजी चुप्पी साधे रहे और इस मुद्दे के पक्ष-विपक्ष में गर्मागर्म बहस होती रही। ज्ञानीजी इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है राजीव गांधी दहशत में आकर उनको पुनः राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दें। फिर उनको उम्मीद बंधी कि शायद विपक्षी और असंतुष्ट कांग्रेसी उनको उम्मीदवार बना लें और वी०वी० गिरि की तरह चुन कर आ जायें। लेकिन साम्यवादियों के पलटा खाने और विद्याचरण शुक्ल ऐंड कंपनी द्वारा विश्वसनीय बहुमत न जुटा पाने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा कर दी कि उनका प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का कोई इरादा नहीं है।

लगता था यहां अब यह अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन फिर बोफोर्स की रिपोर्ट आ गयी और यह साबित हो गया कि तोपों के सौदों में दलाली चली है। इससे पहले प० जर्मनी की पनडुब्बियों के सौदे में दलाली का मुद्दा उठा था ही। जेठमलानी, राजेंद्र पुरी और जार्ज फर्नांडीस फौरन सक्रिय हो गये। उन्होंने राष्ट्रपति से गुजारिश की कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए इजाजत दी जाये। राजीव गांधी को भयभीत करने के लिए ज्ञानी जी को फिर एक चाबुक मिल गया। उस पर वह दम साधकर बैठ गये। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विस्फोट किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने विधिवेत्ताओं से विचार-विमर्श किया है। भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश वाई०वी० चंद्रचूड़, भूतपूर्व विधिमंत्री अशोक सेन और न्यायमूर्ति एस०एम० सीकरी आदि से राय लेने की बात भी ज्ञानीजी ने स्वीकार की। बस फिर क्या था, राजीव गांधी पर फिर खतरा मंडराने लगा। बचाव की तैयारियां शुरू हो गयीं।

लेकिन १८ जुलाई को जैल सिंह के एक साक्षात्कार की खबर शाया हुई। यह साक्षात्कार उन्होंने 'इलस्ट्रेटेड वीकली' को दिया था। इसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह राजीव गांधी पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने जा रहे हैं, "मैं केवल उसी काम की इजाजत दे सकता हूं, जिसका कोई कानूनी आधार हो। मैं उकसावे में कोई काम नहीं कर सकता।" उन्होंने यह कह कर और आश्वस्त कर दिया, "मैंने पहले ही काफी झंझटिया कदम उठाये हैं। कुछ अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ देना चाहिए।"

इसके साथ उन्होंने यह भी जड़ दिया, "यदि राजीव गांधी ने मेरी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनको बर्खास्त कर दूं, उन पर केस दायर करने की इजाजत दे दूं।"

लेकिन फिर उसी दिन दूसरा गुल खिल गया। १८ जुलाई को ऐतिहासिक धमाका हुआ कि स्विट्जरलैंड में अजिताभ बच्चन का अपना निजी मकान है। राजनीतिक घटनाएं तेजी से मोड़ लेने लगीं। पहले अमिताभ बच्चन का इस्तीफा लिया ही जा चुका था। वी०पी० सिंह भी कांग्रेस के बाहर हो गये थे। बोफोर्स के संबंध में भी खबर प्रकाशित हो चुकी थी कि कंपनी नाम बताने के लिए तैयार है, लेकिन राजीव गांधी ऐसा नहीं चाहते। इसी संदर्भ में १८ जुलाई को जार्ज फर्नांडीस ने फिर राष्ट्रपति से गुहार की कि प्रधानमंत्री से वह सार्वजनिक रूप से सफाई मांगें और सफाई न दें, तो उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दें।

१९ जुलाई को राष्ट्रपति विदाई लेने चंडीगढ़ चले गये। वहां वह 'इलेस्ट्रेटेड वीकली' को कही बातों के विपरीत बोल पड़े। उनसे पूछा गया था कि क्या वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देंगे? ज्ञानीजी ने धमाका किया, "यह मामला विचाराधीन है।" जब उनसे कहा गया कि अब उनके पद से हटने में सप्ताह से भी कम समय रह गया है, तो उन्होंने कूटनीतिक लहजे में शंका उत्पन्न करनेवाला उत्तर दिया, "हां फैसला करने के लिए मेरे पास लगभग सप्ताह भर का समय है।"

राष्ट्रपति का यह बयान आना था कि राजीव गांधी के खेमे में आतंक फैल गया। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद वी०पी० सिंह की राष्ट्रपति से मुलाकात ने आग में घी का काम किया। तुरंत जवाबी रणनीति के ताने-बाने बुने गये। २१ जुलाई को सारे कांग्रेस-इ सांसदों को दिल्ली पहुंचने के ताबड़तोड़ अत्यावश्यक संदेश भेजे गये। राज्यों में राष्ट्रपति के आशंकित कदम के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कहा गया। स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन दौड़े और राष्ट्रपति से घंटे भर तक बात की। सांसदों को बुलाने के लिए बहाना था ज्ञानीजी की विदाई और वेंकटरमण के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल होना। लेकिन तीन दिन पहले तुरंत दिल्ली पहुंचने के आदेश के पीछे जो डर था, वह स्पष्ट था।

२१ जुलाई को जैल सिंह के खास आलोचक राज्यमंत्री के०के० तिवारी ज्ञानीजी पर अंधाधुंध बरसे। उन्होंने अपने घर प्रेस सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाया कि वह देश और कांग्रेस को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उनका इरादा खालिस्तान बनाना है। तिवारी के इस कटु प्रहार से लगा कि मामला अब हाथ से निकल गया है और यदि ज्ञानीजी कुछ नहीं भी करना चाहते थे, तो अब करेंगे। उधर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने भी राष्ट्रपति को आगाह किया कि यदि राष्ट्रपति ने कुछ किया, तो नौजवान इसे बरदाश्त नहीं करेंगे।

नाटक का हर दृश्य आशंका, अनिश्चितता, सनसनी और रहस्य पैदा करता जा रहा था कि अचानक २२ जुलाई को 'एंटीक्लाइमेक्स' हो गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेठमलानी, जार्ज फर्नांडीस और राजेन्द्र पुरी को सूचित किया कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने की वह इजाजत नहीं दे सकते। पत्र २१ जुलाई को लिखा गया था। उस दिन प्रधानमंत्री ज्ञानीजी से मिले थे, बातें क्या हुईं यह तो पता नहीं। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री ने इस कदम के खतरों से राष्ट्रपति को आगाह किया होगा। दूसरी ओर के०के० तिवारी की 'बलि' चढ़ाने का वायदा भी शायद किया गया था। फोतेदार ने उनका इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए २३ जुलाई को उनकी छुट्टी कर दी गयी। अफवाह बाजों का कहना है कि कोई सौदा हुआ है। लेकिन इस तरह की ओछी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। हां, ज्ञानी जैल सिंह ने अपने आखिरी क्षणों में राजीव गांधी की नींद हराम करके यह जता दिया कि राष्ट्रपति मात्र 'रबर मोहर' नहीं है। ज्ञानीजी का यह आखिरी सबक शायद ही राजीव गांधी भूल पायें।

—विशेष प्रतिनिधि

अमिताभ बच्चन

इस्तीफा क्यों देना पड़ा?

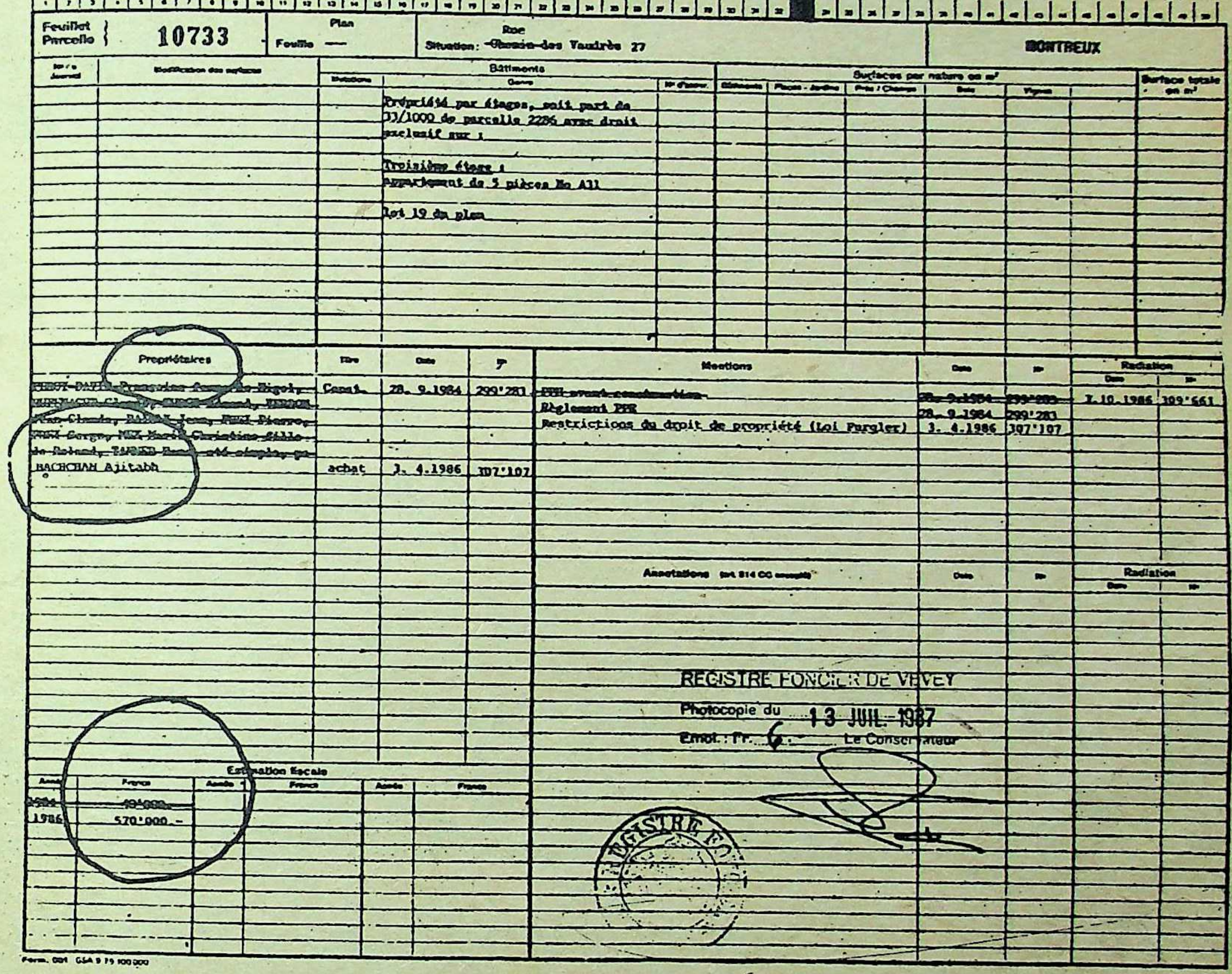

Feuillet Parcelle 10733

Plan Feuille —

Rue Situation: ~~Chemin~~-des Vaudrès 27

MONTREUX

Bâtiments

Propriété par étages, soit part de 33/1000 de parcelle 2286 avec droit exclusif sur :

Troisième étage :
Appartement de 5 pièces No A11

Lot 19 du plan

Propriétaires

~~[illegible]~~

BACHCHAH Ajitabh — achat — 3. 4.1986 — 307'107

Const. — 28. 9.1984 — 299'283

Mentions

~~PPE avant construction~~ — ~~28. 9.1984~~ — ~~299'283~~ — Radiation: 1.10.1986 — 309'661

Règlement PPE — 28. 9.1984 — 299'283

Restrictions du droit de propriété (Loi Furgler) — 3. 4.1986 — 307'107

Annotations (art. 814 CC excepté)

Estimation fiscale

~~1984~~ — ~~494'000~~

1986 — 570'000.-

REGISTRE FONCIER DE VEVEY
Photocopie du 13 JUIL. 1987
Emol.: Fr. 6.-
Le Conservateur

Form. 001 GSA 9 79 100 000

सबूत: स्विट्जरलैंड में अजिताभ द्वारा मकान खरीदने का दस्तावेज

'माया' (१५ जुलाई, १९८७) ने पहले ही कह दिया था कि अमिताभ बच्चन की दोस्ती राजीव गांधी के लिए महंगी पड़ेगी। अब वह दस्तावेज सामने आ गया है, जिससे पता चला है कि अमिताभ के भाई अजिताभ ने स्विट्जरलैंड में ८५ लाख रुपये का मकान खरीदा है। इस दस्तावेज के प्रकाशित होने के एक दिन पहले ही अमिताभ बच्चन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा-प्रकरण और उसके दूरगामी प्रभावों का जायजा:

माहौल तो आम दिनों जैसा ही था, लेकिन घटना आम नहीं थी। अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री-निवास के स्वागत कक्ष से बाहर निकलते हैं। बाहर इंतजार कर रही भीड़ हाथ जोड़ कर उनकी ओर बढ़ती है। लेकिन अमिताभ ने न अभिवादन स्वीकार किया, न मुस्कराकर अपने प्रशंसकों को उपकृत किया, बल्कि आगे बढ़ गये। उन्होंने प्रधानमंत्री-निवास में प्रवेश का टोकन गार्ड को थमाया और साधारण-सी फियट में बैठ कर चलते बने। आज उनकी अल्पायु राजनीति का अंतिम दिन था। कुछ क्षण पहले ही उनके परम मित्र ने उनसे संसद की सदस्यता से इस्तीफा लिया था। लेकिन यह तो आफत की शुरुआत है।

तीस माह पहले उन्होंने महानायक के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था और १७ जुलाई, १९८७ को उन्हें महाखलनायक के रूप में राजनीति से बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ा। राजीव गांधी के वह महाबली-हंता (जायंट-किलर) थे, लेकिन स्वयं राजीव गांधी ने अपने हाथों से ही राजनीति में उनका सितारा गुल कर दिया। अवकाश के क्षणों में राजीव गांधी उनका इस्तेमाल केवल अपने इतालवी रिश्तेदारों के मनोरंजन के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि अपने नवजात विचारों पर भी उनकी राय लेते थे। लेकिन राजीव गांधी ने अपने दोस्त की 'निर्णायक' बलि चढ़ाने में थोड़ी देर कर दी। इसलिए इससे जो मकसद वह सिद्ध करना चाहते थे, वह नहीं हो पाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और अनुभवी राजनेता हरिदेव जोशी का कहना ठीक ही है, "अगर वह (बच्चन) पहले इस्तीफा देते, तो कांग्रेस का ज्यादा भला करते।" तीन महीने तक अपयशकारी निंदा अभियान छिड़े रहने के बाद यह इस्तीफा दिया गया है। इस दौरान अमिताभ ने अनेक साक्षात्कारों में परस्पर विरोधी बातें कही हैं। (देखिए बाक्स) ये साक्षात्कार ज्यादातर उन्हीं लोगों को दिये गये हैं, जिनको वह अपना मानते हैं।

राजनीति में क्या काम है...: अमिताभ 'शहंशाह' मे.।

लेकिन बजाय इसके कि इन साक्षात्कारों से वह अपनी जान बचाते, वह और ज्यादा पंक में धंसते चले गये। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोस्त राजीव गांधी को भी गले में घोटालों के पत्थर लटका कर राजनीतिक सैलाब में छोड़ दिया था। यह स्थिति उन कांग्रेसियों को भी चुभने लगी थी जो आमतौर पर अपनी मोटी चमड़ी पर सत्ता की मालिश करके पांच साल तक घोड़े बेच कर सोये रहते हैं। उन्होंने महसूस किया कि बच्चन के कारण उनको चुनाव जितानेवाले व्यक्ति की विश्वसनीयता तेजी से नीचे जाने लगी है। फल यह हुआ कि ज्यादातर लोग बच्चन के खून के प्यासे हो गये।

इस्तीफा देने के कुछ दिन पहले जब वह राष्ट्रपति-चुनाव में मत देने दिल्ली आये थे, तो एक कांग्रेसी सांसद ने 'माया' से कहा था, "मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मुझे बच्चन के साथ देखे।" दूसरे ने भी ठीक ऐसी ही बात कही थी, "हममें से ज्यादातर लोग सेंट्रल हाल में उनसे दूर रहना पसंद करते हैं।" अमिताभ के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन इन घाघ राजनेताओं को यह अहसास होने लग गया था कि वी०पी० सिंह के अभियान का जादू जनता के सिर पर चढ़ कर बोलने लगा है। क्योंकि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं था कि अजिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड में पहुंच चुके हैं। दोनों भाइयों की इस बात पर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा

क्या अमिताभ ब्रीच कैण्डी अस्पताल को याद रखेंगे ?

ब्रीच कैंडी अस्पताल के प्रशासक निदेशक पी०एस० कैकर ही वह व्यक्ति हैं जो अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ अस्पताल को मिलनेवाली दानराशि का काम भी देखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि जिस अस्पताल ने अमिताभ को सफलतापूर्वक मौत के मुंह से निकालने में अभूतपूर्व मदद की, उसे एक रुपये भी दान में देने के बजाय अमिताभ द्वारा धनीमानी हिंदुजा के नेशनल अस्पताल को पांच लाख रुपए दान में देने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?—तो श्री कैकर का कहना था, "एक अस्पताल के नाते अपने मरीजों को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। हम अपेक्षा नहीं रखते कि इन सेवाओं से प्रसन्न होकर हमारा मरीज हमें दान दे। निःसंदेह यह स्वाभाविक है और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो मरीज अस्पताल की सेवाओं और इलाज से ठीक हो जाते हैं, वे ऐसा सोचते हैं और सहयोग भी देते हैं। चूंकि, यह अस्पताल धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित है, इसलिए हम ऐसे सहयोग को सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका यकीनन यह अर्थ नहीं है कि जो ऐसा नहीं सोचते हम उनके खिलाफ हो जायें या इसका बुरा मानें।"

कैकर ने स्पष्ट किया कि अस्पताल को दान देनेवालों की सूची में एक भी व्यक्ति फिल्म जगत का नहीं है। कैकर की महिला सहयोगी ने बतलाया, "फिल्मी लोग जब हमसे बातें करते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। वे कहते हैं—हम आपको हमेशा याद रखेंगे, लेकिन इस मौखिक बधाई के अलावा वे और कुछ नहीं करते।"

अमिताभ बच्चन ने हाल ही अपनी एक भेंटवार्ता में इच्छा जाहिर की है कि वह 'शहंशाह' फिल्म के प्रीमियर से होनेवाली आय 'ब्रीच कैण्डी अस्पताल' को दान में देंगे। यदि उनका यह इरादा है, तो वह इस कार्य को ३१ मार्च, १९८८ तक पूरा कर लें, क्योंकि अस्पताल को धारा ३५(१) II के अंतर्गत आयकर में मिली छूट उस दिन समाप्त हो रही है।

—किरण मेहता

था कि वे दूध के धुले हैं। लेकिन दोस्ती के बंधन फिर भी अटूट थे। इसका मूल कारण था दोस्त-पत्नियों का काफी समीप होना। इसलिए राजीव गांधी आखिरी दम तक अमिताभ को अलग करने से हिचकते रहे। शुरू में तो उन्होंने बच्चन-बंधुओं के खिलाफ लगे आरोपों पर कान तक नहीं दिया। जिस समय संसद में अजिताभ के कारनामों पर हंगामा मचा हुआ था, उस दौरान राजीव गांधी, अजिताभ, उनकी पत्नी रमोला और चार बच्चों को साथ लेकर अंडमान में छुट्टी बिताने चले गये। यह एक प्रकार से लोगों को यह जताना था मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि अजिताभ के बारे में वे क्या कह रहे हैं। प्रसिद्ध पत्रकार एस० मुलगांवकर ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजीव गांधी के दोस्त जैसे उच्च कोटि के नागरिक और देश के बाकी लोग निम्न कोटि के नागरिक हों, राजीव गांधी के दोस्तों को शायद यह अघोषित अधिकार भी मिला हुआ था कि वे चाहे जो कर सकते हैं।

जब संसद के बजट सत्र में एक-के बाद-एक घोटाले उघड़ने लगे, तो प्रधानमंत्री के खेमे ने अपनी रणनीति को आक्रामक रूप दे दिया। इस रणनीति से साफ ध्वनित होता था कि जैसे राजीव गांधी के दोस्तों पर उंगली उठाना वर्जित हो। अमिताभ ने साफ इनकार कर दिया कि उनका बोफोर्स या किसी अन्य सौदे में कोई हाथ है। ऐसी स्थितियों से संवेदनशील वी०पी० सिंह का उत्तेजित होकर मंत्रिपरिषद से हटना इस खेमे के लिए और भी राहत की सांस थी। वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षित होने के कारण इस खेमे के लोगों को लगा कि अब संकट टल गया। वे इतने सुनिश्चित हो गये कि गर्मी के मौसम की शुरुआत में जब अजिताभ भारत आये, तो उन्होंने और उनके सांसद भाई अमिताभ ने अपने साक्षात्कारों में कहा कि मांत्रों (स्विट्जरलैंड) में मात्र ढाई कमरे का छोटा-सा फ्लैट है—वह भी किराये का। और यह किराया भी अजिताभ के नियोजकों की ओर से दिया जा रहा है। दोनों भाइयों ने इस मामले में काफी आक्रामक रुख भी अपनाया। उनका कहना था कि उनको अपने व्यापार के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन अब इसी बयान के कारण दोनों भाई संकट में फंस गये हैं। संसद और संसद के बाहर अमिताभ बच्चन जो कुछ कह रहे थे, तथ्य उसके विपरीत सिद्ध हुए हैं। जाहिर है मानसून सत्र में इस स्थिति का सामना करना संभव नहीं था और अमिताभ बच्चन के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। विडंबना तो यह है कि दस दिन पहले ही अमिताभ ने कहा था कि उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता।

क्या राजीव को भी फंसायेंगे ? : माता-पिता के साथ अमिताभ

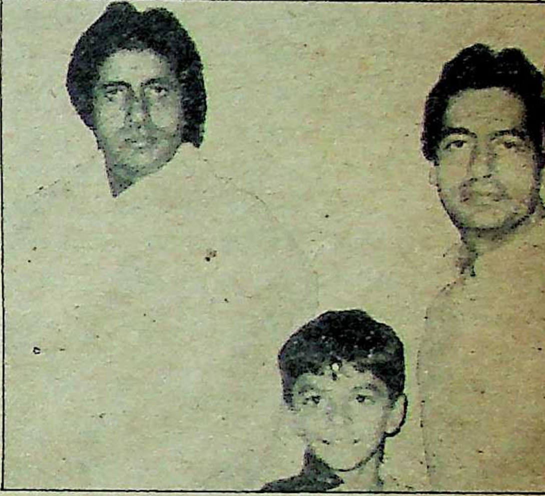

स्विस घोटाला ले डूबा : अमिताभ-अजिताभ

यों तो अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि वह अपने दोस्त के लिए यह त्याग कर रहे हैं, लेकिन शायद वह इस खबर से बेखबर नहीं रहे होंगे कि जेठमलानी ने पक्का सबूत हासिल कर लिया है। इस खबर से ही उनके हाथों के तोते उड़े होंगे। लेकिन अपने को त्याग की मूर्ति सिद्ध करते हुए उन्होंने १७ जुलाई, १९८७ की दोपहर को इस्तीफा दिया। दूसरे दिन 'इंडियन एक्सप्रेस' में वह दस्तावेज छपा, जिसमें स्विट्जरलैंड में अजिताभ द्वारा फ्लैट खरीदने की पुष्टि होती है। जाहिर है सरकार को पहले से ही सूचना मिल गयी थी।

राजीव खेमे की चिंता का एक कारण और भी था। चंद्रास्वामी के खास साथी मामाजी—कैलाशनाथ अग्रवाल—भी दिल्ली में फिर नमूदार हो गये। गोयनका के गेस्ट हाउस पर छापे के तुरंत बाद मामाजी बाहर चले गये थे। मामाजी के बारे में यह संदेह किया जाता है कि वही वह कथित रिपोर्ट लेकर आये थे जो विश्वकुख्यात हथियारों के दलाल अदनान खशोगी ने लेबनानी जासूसी संस्था के माध्यम से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि खशोगी ने इस जासूसी संस्था को सोनिया गांधी के पीछे उस समय लगाया था, जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए गयी थीं। इस जासूसी ने सोनिया गांधी की गतिविधियों की रिपोर्ट खशोगी को दी थी और वह रिपोर्ट मामाजी के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंची थी। इसी तरह अजिताभ के स्विट्जरलैंड स्थित मकान के संबंध में जो दस्तावेज जेठमलानी लाये हैं, उसके बारे में भी रोचक किस्सा है। कहीं हवाई अड्डे के अधिकारियों को दस्तावेज का पता न लग जाये और वहीं उसे वे जब्त न कर लें, इसलिए जेठमलानी ने इस दस्तावेज़ को यहां लाने का रहस्यमय रास्ता अपनाया।

सत्रों का कहना है कि जेठमलानी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, उसे वह अपने साथ नहीं लाये। उसे वह वहीं छोड़ आये और बाद में वह 'फैक्सीमिल मशीन' के

जरिये दिल्ली आया। ऐसा शक है कि इसी प्रक्रिया में इस दस्तावेज की खबर सरकार या अमिताभ को मिल गयी। बंगलौर में शूटिंग कर रहे अमिताभ को तुरंत दिल्ली बुलाया गया और इस्तीफा देने की सलाह दी गयी। उम्मीद थी कि इससे कांग्रेसियों का गुस्सा ठंडा होगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि राजीव गांधी को यदि किसी के खिलाफ ठोस सबूत दिये जायें, तो चाहे वह कितना ही बड़ा और करीबी क्यों न हो, वह उसे नहीं बख्शने वाले। लेकिन १७ जुलाई की शाम को अमिताभ बच्चन के 'त्याग' और राजीव गांधी की न्यायप्रियता की 'धाक' उस धमाके से धूमिल पड़ गयी जब वी०पी० सिंह ने राज्यसभा और कांग्रेस-इ की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इससे संकट और गहरा गया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, "मैं अमिताभ बच्चन को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने कहा था कि कोई आरोप सिद्ध हो गया, तो वह इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया।" आरिफ की इस बधाई में यह तंज छिपा हुआ था कि यह इस्तीफा विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लघंन की स्वीकृति है। वह कहते हैं, "इससे प्रधानमंत्री की यह बात भी पुष्ट हो गयी कि कोई दलाल बीच में नहीं था। बच्चन और स्वयं प्रधानमंत्री सौदों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें दलाल कैसे कहा जा सकता है।"

जब स्वयं प्रधानमंत्री साफ फंस रहे हों, तो बच्चन-बंधुओं के खिलाफ कार्यवाही करने की उद्घोषणा के अलावा राजीव गांधी के पास कोई चारा नहीं था। राजीव गांधी के एक तरफ कुआं था, तो दूसरी तरफ खाई। यदि वह कार्यवाही नहीं करते, तो जनता के कोप का सामना करना पड़ता और डूबती नाव से कांग्रेसियों की भगदड़ शुरू होती। दूसरी ओर कार्यवाही से उत्तेजित होकर बच्चन-परिवार द्वारा 'भेद खोलने' का भय था। यह भय सही है या गलत, लेकिन बच्चन-परिवार का स्वभाव प्रतिशोधात्मक माना जाता है। राजीव गांधी के दुश्मनों को इसी की उम्मीद है और वफादारों को इसी का 'भय' है।

इस संदर्भ में एक पार्टी पदाधिकारी ने 'माया' से कहा, "यदि अमिताभ बच्चन बिना साक्षात्कार दिये तीन महीने पहले इस्तीफा दे देते, तो कुछ उम्मीद बनती। अब ऐसा लगता है कि राजीवजी चोर की रक्षा कर रहे थे और अब इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी जान आफत में पड़ गयी है।" जो दस्तावेज 'इंडियन एक्सप्रेस' ने प्राप्त किया, वह सरकार क्यों नहीं प्राप्त कर सकी? दो में से एक ही कारण हो सकता है— या तो राजीव गांधी को बच्चन-बंधुओं पर अंधविश्वास था या फिर वह उनको बचाने में लगे थे। लेकिन अब पोल खुल गयी, तो राजीव गांधी के पास बच्चन को इस्तीफा देने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह काम उस समय हुआ, जब काफी देर हो चुकी थी।

अमिताभ बच्चन

इससे बढ़कर क्या होगा कि चाहे दोनों दोस्त एक दूसरे के खिलाफ बोलें या न बोलें, लेकिन एक दूसरे से भयभीत तो रहेंगे ही?

अमिताभ ने कहा था...

८ फरवरी, १९८७

वह (अजिताभ) स्विट्जरलैण्ड में अप्रवासी भारतीय के रूप में रह रहा है और अपना औषधि का धंधा कर रहा है।

—टाइम्स आफ इंडिया, सनडे रिव्यू

३० अप्रैल, १९८७

अजिताभ वहां (स्विट्जरलैण्ड) एक फर्म का कर्मचारी है। उन्होंने बड़ी सावधानी से अजिताभ के चरित्र की जांच की थी। वह वहां बिक्री और उत्पादन का कार्य करेगा और यहां से कच्चा माल मुहैया करायेगा। वहां की नागरिकता लेने या वहां बसने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्विट्जरलैण्ड में प्रवेश पा जाना वस्तुतः असंभव है। वह वहां सिर्फ 'वर्क परमिट' प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसमें कहीं धन का भुगतान नहीं करना है।

—इंडिया टुडे

२९ जून, १९८७

अजिताभ एक अप्रवासी भारतीय है जो औषधि व्यवसाय के सिलसिले में गत अक्तूबर से स्विट्जरलैण्ड में है। उसने स्विट्जरलैण्ड या किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है। मेरा और मेरे भाई का कोई निजी या संयुक्त खाता विदेश के किसी बैंक में नहीं है, जैसाकि समाचार पत्रों में आरोप लगाया गया है। और विदेशी मुल्कों में हमने कोई संपत्ति नहीं बनायी है।

—यू०एन०आई०

जिस समय अजिताभ बच्चन ने स्विट्जरलैंड में मकान खरीदा, क्या उस समय राजीव गांधी को उन्होंने यह बात बतायी थी? चाहे केस जेठमलानी दायर करें या कार्टूनिस्ट राजेन्द्रपुरी, सुनवायी के समय यह सवाल जरूर उठेगा। मामला कोई चलाये, राजीव गांधी का नाम जरूर घसीटा जायेगा। मुख्य निशाना राजीव गांधी ही हैं, इसलिए अजिताभ के खिलाफ चले मामले का इस्तेमाल उनकी छवि को तबाह करने के लिए अवश्य किया जायेगा। इसका सीधा-सा तरीका यह है कि बच्चन-बंधुओं में प्रतिशोध की भावना को भड़काया जाये, जिससे वे गवाही के समय अपने 'दोस्त' की ओर उंगली उठायें। यह आशंका 'वफादारों' की नींद हराम किये हुए है।

बच्चन-परिवार के एक करीबी सूत्र का कहना है कि माता-पिता अपने दोनों लड़कों के अपमान को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस-इ के एक महत्वपूर्ण सांसद का कहना है कि दो महीने पहले अमिताभ बच्चन कड़ी शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने बिना कुछ पाये राजीव गांधी के लिए सब कुछ खो दिया है। दूसरी ओर जया अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थीं। सांसद के अनुसार, "उसे (जया) यह नागवार लग रहा था कि प्रधानमंत्री निवास से लगातार आने वाले फोन अमिताभ को चिंतित और जगाये रखते हैं।" अगर दो महीने पहले यह स्थिति थी, तो अभियोग चलने पर यह विद्रोह में नहीं बदल जायेगी कौन कह सकता है। उनको जो क्षति होनी थी, वह हो चुकी है। यहां तक कि चाहे वे यह झूठ भी बोलते हैं कि यह सौदा 'बेनामी' है, तो भी राजीव को क्षति पहुंचाने के लिए काफी है। इससे बढ़कर क्या होगा कि चाहे दोनों दोस्त एक दूसरे के खिलाफ बोलें या न बोलें, लेकिन एक दूसरे से भयभीत तो रहेंगे ही?

बताया जाता है कि इस तरह की कोशिश हो रही है कि अपने लड़कों को बचाने के लिए हरिवंश राय बच्चन और श्रीमती तेजी बच्चन से कोई बयान जारी करवाया जाये। जाहिर है अन्ततः यह राजीव गांधी को क्षति पहुंचायेगा। वैसे यह आसान नहीं है, क्योंकि पिछले दो साल से बिना पड़ोसियों की परवाह किये, वे अभूतपूर्व विशेषाधिकार भोगते रहे हैं। पिछले १० दिन से उनके गुल मोहर पार्क निवास के आसपास टेलीफोन ठप पड़े बताये जाते हैं, क्योंकि बच्चन-परिवार के लिए टेलीफोनों की खास व्यवस्था की जा रही है। हाल में उनके घर के सामने 'स्पीड ब्रेकर' बनाये गये हैं, जो वहां से गुजरनेवाली कारों के अंजर-पंजर ढीला कर रहे हैं। जया बच्चन को भी विमान सेवाओं में खास सुविधाएं और प्रतिष्ठा बख्शी जाती है, क्योंकि वह विमान परिचारिकाओं के लिए साड़ी और ब्लाउज के चयनकर्ताओं में हैं और विमानों की आंतरिक साज-सज्जा की सलाहकार हैं। जया की सास संस्कृति की नयी संरक्षिका के रूप में उभरी हैं। यह बात दूसरी है कि जितनी तेजी से ऊपर वे उठे हैं, उतनी तेजी से गिरने का क्रम भी शुरू हो गया है। हरिवंश राय बच्चन में बैठे दार्शनिक ने जीवन के उस पार की रहस्यमय दुनिया को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देते हुए कहा है: "इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा।" लेकिन उनमें बैठा पिता यह कभी नहीं चाहेगा कि उनके दोनों पुत्रों को मुकदमे के उस पार की दुनिया का सामना करना पड़े। यह डर न गांधी को चैन लेने देगा और न उनके 'मित्रों के गिरोह' को। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है और बच्चन-परिवार इसका अपवाद नहीं हो सकता।

—विजय दत्त, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ

अजीत सिंह की राजनीतिक हैसियत !

हरियाणा में बिलकुल सफाये के बाद चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह के भविष्य पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। क्या हरियाणा की हार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अजीत सिंह का कोई भविष्य नहीं है ? क्या वह अपने पिता के जनाधार को अपना जनाधार बना पायेंगे ?

"वेद मारवाह (दिल्ली के पुलिस कमिश्नर) को फोन मिलाओ, वेद मारवाह को फौरन फोन मिलाएं"—लोकदल अध्यक्ष के कमरे में लगे टेलीफोन का चोंगा पटकते हुए उत्तेजित सुब्रह्मण्यम स्वामी खुद ही कार्यालय के एक कोने में पी०बी०एक्स० आपरेटर के कमरे की ओर दौड़े। जिस कमरे में कभी लोकदल के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी सिंह बैठा करते थे, उसके दरवाजे एक बार खुल कर फिर बन्द हो गये। अन्दर चौधरी साहब की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके इकलौते पुत्र अजीत सिंह। जो लोकदल (अजीत सिंह गुट) के अध्यक्ष हैं। वहां मौजूद थे महामंत्री सत्यप्रकाश मालवीय सहित दल के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारी। पूरे दफ्तर में एक अफरातफरी का माहौल था और गेट पर ही खड़ी थीं पुलिस की दो वायरलेस लगी जीपें। दफ्तर के एक कोने में बने कमरे के बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर कुछ रायफलधारी सिपाहियों के साथ मुस्तैदी से मुआयना कर रहा था और कार्यरत कर्मचारियों तथा छुटभैये नेताओं-कार्यकर्ताओं के मध्य खुसफुसाहट जारी थी।

संकटग्रस्त विरासत : लोकदल-अ अध्यक्ष अजीत सिंह

सत्यप्रकाश मालवीय

> "उ०प्र० में हम लोकदल-ब की रीढ़ तोड़ चुके हैं। उन २८ में अब भगदड़ बची है। कुछ ही दिनों में मुलायम सिंह के साथ के काफी विधायक हमारे साथ आ जायेंगे।"

किंतु शाम तक १५, विंडसर प्लेस स्थित लोकदल-अ के इस राष्ट्रीय कार्यालय का माहौल रोजमर्रा की तरह ऊंघते-ऊबते सुस्त अन्दाज में बदल चुका था। लोकदल के शायद सबसे पुराने चपरासी व चौधरी साहब के विश्वसनीय नौकर विजेंदर द्वारा दिल्ली पुलिस को लिखवायी गयी एक रिपोर्ट से उठा यह बवंडर शाम तक शांत हो चुका था। विजेंदर इसी कार्यालय के सर्वेंट क्वार्टर में काफी समय से रहता आ रहा था। किंतु लोकदल के विभाजन के कुछ समय बाद ही अजीत सिंह ने विजेंदर को नौकरी से निकाल दिया था। अजीत सिंह गुट के कुछ लोगों का मानना था कि विजेंदर बहुगुणाजी का आदमी बन गया है तथा यहां की सारी सूचना वहां तक पहुंचाता है। इसके तुरंत बाद ही विजेंदर से सर्वेंट क्वार्टर खाली करने को कहा गया। उसके द्वारा ऐसा न करने पर जबरदस्ती उसका सारा सामान उठा कर बाहर फेंक दिया गया। जिसके जवाब में विजेंदर ने अजीत सिंह सहित दल के कई नेता-कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस में, जबरदस्ती घर में घुस कर लूटपाट करने, मारपीट करने, धमकी देने तथा घर से बेदखल कर देने की रिपोर्ट दायर कर दी। उस दिन सुबह सुब्रह्मण्यम स्वामी से लेकर अजीत सिंह तक लोकदल-अ के नेताओं में फैली उत्तेजना, रोष व अफरा-तफरी का कारण 'विजेंदर' द्वारा पुलिस में दायर की गयी यही रिपोर्ट थी जो शाम तक रफा-दफा हो गयी।

निश्चित तौर पर यह कोई महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय घटना नहीं है। फिर इसके यहां उल्लेख का मकसद है, तो सिर्फ यही कि हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से आज तक लोकदल-अ के राष्ट्रीय कार्यालय में घटने वाली यह इकलौती घटना (यदि इसे एक घटना माना जाये तो) है, जिसने इस दफ्तर की जड़ता को, कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन सही झकझोरा था। अन्यथा अविभाजित लोकदल की घमासान लड़ाई और टूट के बाद से १५ विंडसर प्लेस में फैले अधूरेपन का अहसास लगातार बढ़ता ही रहा है। यह उस दिन और भी गहराया था, जब दल के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह अपनी लम्बी बीमारी के बाद दिवंगत हो गये। इसके तुरंत बाद ही हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस पार्टी को भयानक पराजय का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी के साथ गठजोड़ कर इस मोर्चे ने हरियाणा में ७२ उम्मीदवार खड़े किये थे, जिनमें एक भी उम्मीदवार विजयी नहीं हो सका। मोर्चे के सिर्फ तीन उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा सके, शेष ६९ उम्मीदवारों की जमानतें तक नहीं बचीं। लोकदल-अ द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों में ५२ की जमानतें जब्त हुईं। पराजय-दर-पराजय की इन खबरों से इस पार्टी को सबसे ज्यादा सदमा तब लगा, जब रोहतक लोकसभा उपचुनाव में गायत्री देवी (चौ०चरण सिंह की पत्नी) की हार की खबर दिल्ली पहुंची। इसके बाद से ही १५ विंडसर प्लेस के माहौल में जहां एक तरफ हताशा की गहरी छाया और स्पष्ट नजर आने लगी, वहीं दल के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी की लहर फैलनी शुरू हो गयी। राजधानी के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर अजीत सिंह और उनके दल को लेकर तरह-तरह की राय, उनके राजनीतिक भविष्य पर अटकलों, समीक्षाओं व अफवाहों का दौर तेज हो गया। "अजीत सिंह कांग्रेस में जा रहे हैं", "अजीत सिंह राजनीति से संन्यास लेकर दुबारा डी०सी०एम० की नौकरी शुरू कर देंगे, चौधरी साब के लड़के ने तो हरियाणा में नाक कटा दी"; जैसी टिप्पणियों से लेकर "अजीत सिंह जनता पार्टी में जा रहे हैं" या "वह तो हरियाणा था, उ०प्र०—बिहार में अजीत सिंह बहुगुणा को जबरदस्त पटखनी देंगे" जैसी बातों का बाजार गर्म हो गया।

सुब्रह्मण्यम

> "वह (लोकदल बहुगुणा) कोई राजनीतिक दल नहीं है। कुंभ का मेला है, कुछ समय के लिए अलग-अलग जगह से तरह-तरह के लोगों की भीड़ आकर इकट्ठा हो गयी है जो नहा-धोकर वापस अपने घरों को चले जायेंगे।"

अस्तित्व का सवाल : हरियाणा में विजय के तुरंत बाद लोकदल-ब का अध्यक्ष पद संभालते ही हेमवती नंदन बहुगुणा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा—"कौन अजीत सिंह और कैसी उनकी पार्टी?" तो दूसरी जगह उन्होंने लोकदल-अ के संबंध में प्रश्न पूछने तक पर आपत्ति की— "आप लोग (पत्रकार) खामखां उनके विषय में बात कर रहे हैं। मैं उनके विषय में कुछ बोल कर उन्हें बेवजह महत्व नहीं देना चाहता और न ही मैं उसे कोई राजनीतिक दल मानता हूं।" वहीं दूसरी तरफ लोकदल-अ के प्रश्न को लेकर पूरी जनता पार्टी दो विपरीत खेमों में बंट गयी है। जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर व उनके समर्थकों को अजीत सिंह व उनके दल में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने की संभावना दिख रही है, वहीं जार्ज फर्नांडीस-बीजू पटनायक के समर्थकों का मानना है कि अजीत सिंह के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ होने से पहले ही अंत शुरू हो गया है तथा निकट भविष्य में वह अपनी बची-खुची राजनीतिक पूंजी भी गवां बैठेंगे। इसी तरह अजीत सिंह के कथित कांग्रेसी संबंधों को लेकर भी पक्ष-विपक्ष दोनों में ही विभिन्न मत सुने जा सकते हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान चौ० देवीलाल सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय प्रेस के सामने अजीत सिंह पर यह आरोप लगा चुके हैं कि "उन्होंने कांग्रेस से दो करोड़ रुपया लिया है।"

इन आरोपों-प्रत्यारोपों, अफवाहों व अटकलों से घिरे अजीत सिंह अपने राजनीतिक जीवन का एक वर्ष पूरा कर चुके हैं। इस एक वर्ष में उनके द्वारा उठाये गये राजनीतिक कदमों, अपनायी गयी कार्यशैली, अपने इर्द-गिर्द इकट्ठे किये गये राजनीतिक-गैरराजनीतिक मित्रों, व दिये गये वक्तव्यों की विवेचना तथा उ०प्र० तथा बिहार में वर्तमान स्थिति में मौजूद राजनीतिक शक्तियों के समीकरण की समीक्षा के आधार पर अजीत सिंह के राजनीतिक भविष्य के विषय में कोई ठोस भविष्यवाणी भले ही न की जा सके, किंतु गति और दिशा के संबंध में एक अनुमान अवश्य ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

"भविष्य तो हमारा ही है" —लोकदल के राष्ट्रीय कार्यालय में चौधरी चरण सिंह की कुर्सी पर बैठे अजीत सिंह जब यह वाक्य कह रहे थे, तब उनके चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं था, जिस पर किसी की निगाह टिक सके। न आत्मविश्वास की झलक और न ही पराजय से उत्पन्न नैराश्य भाव। सिर्फ एक सपाट चेहरा, जिसके पीछे टंगी महात्मा गांधी की तस्वीर पर किसी के द्वारा छिड़की गयी स्याही के काले दाग अवश्य ज्यादा गहरे नजर आ रहे थे।

कड़ुवे अनुभव : सिर्फ एक साल पहले नये, ताजे और साफ-सुथरे चेहरे के साथ राष्ट्रीय राजनीति में उतरे अजीत सिंह के अब तक के राजनीतिक जीवन के अनुभव कड़ुवे रहे हैं। इस छोटे से समय में उपलब्धियों के नाम पर उनके खाते में जहां एक तरफ राज्यसभा की सदस्यता, अविभाजित लोकदल के महासचिव तथा विभाजित लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकदल की टूट, हरियाणा की हार, कथित कांग्रेसी संबंधों के आरोप व हेमवती नंदन बहुगुणा,

रशीद मसूद खां

न केवल अजीत सिंह, बल्कि सत्यप्रकाश मालवीय, रशीद मसूद तथा सुब्रह्मण्यम स्वामी भी लोकदल-अ के भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। साथ ही वे यह भी दावा पेश करते हैं कि लोकदल-ब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायेगा।

देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, नाथूराम मिर्धा तथा मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज लोकदलीय नेताओं से मोल ली गयी राजनीतिक दुश्मनी है।

ऐसी स्थिति में अपने छोटे से राजनीतिक अनुभव, तीन विपरीत राजनीतिक पृष्ठभूमि व सोच के राष्ट्रीय महासचिवों-सत्यप्रकाश मालवीय, रशीद मसूद तथा सुब्रह्मण्यम स्वामी, अजय सिंह तथा डा० राज सिंह तैलान जैसे विदेश से लौटे युवा मित्र-सलाहकारों, उ०प्र० के ५२ विधायकों तथा विरासत में मिले चौ० चरण सिंह के आधे-अधूरे जनाधार के बल पर ही यदि अजीत सिंह भविष्य पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो उस पर राजनीतिक समीक्षकों को संदेह होना स्वाभाविक है।

गत एक वर्ष के दौरान, उ०प्र० में मुलायम सिंह के विरुद्ध सफल विद्रोह के अतिरिक्त कोई भी ऐसी राजनीतिक घटना नहीं है, जिसे अजीत सिंह में सूझबूझ भरे तेजतर्रार नेतृत्व की क्षमता के सबूत के तौर पर गिनाया जा सके।

लोकदल की राष्ट्रीय स्तर पर टूट के ६ महीने बीत जाने के बाद भी अजीत सिंह के साथ उ०प्र० को छोड़कर किसी भी प्रदेश में एक भी विधायक औपचारिक रूप से नहीं है। हरियाणा में अजीत सिंह के साथ आये सातों विधायक चुनाव हार चुके हैं। बिहार तथा राजस्थान में अजीत सिंह समर्थक विधायक अभी संख्या एक तिहाई तक नहीं बढ़ा पाये हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा सदस्यता खतम होने के भय से न तो वह खुलकर सामने आये हैं, और न ही उनकी सही संख्या की प्रमाणिक जानकारी मिल पा रही है। यद्यपि दल के महासचिव रशीद मसूद के अनुसार बिहार के ४५ लोकदलीय विधायकों में १४ उनके साथ हैं, किंतु वे तब तक खुलकर सामने नहीं आयेंगे, जब तक उनकी संख्या १६ नहीं हो जाती। उन्हें शीघ्र ही दो विधायकों के अपने साथ आने की प्रतीक्षा है। इसी प्रकार राजस्थान के २७ विधायकों में उनका दावा है कि ६ विधायक उनके साथ हैं। वहां उन्हें तीन विधायकों की प्रतीक्षा है। लोकसभा में इस दल का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी सदस्य नहीं है। लोकदल की टूट के बाद अजीत सिंह के नेतृत्व में लड़े गये अब तक सभी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में दल का कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ है।

आस्वस्ति : इसके बावजूद न केवल अजीत सिंह, बल्कि सत्यप्रकाश मालवीय, रशीद मसूद तथा सुब्रह्मण्यम स्वामी भी लोकदल-अ के भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। साथ ही वे यह भी दावा पेश करते हैं कि लोकदल-ब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायेगा और अधिकांश लोकदल कार्यकर्ता उनके साथ वापस आ जायेंगे। सुब्रह्मण्यम स्वामी तो लोकदल-ब को राजनीतिक दल मानने को ही तैयार नहीं हैं। उनका 'माया' से कहना था, "वह (लोकदल बहुगुणा) कोई राजनीतिक दल नहीं है। कुंभ का मेला है, कुछ समय के लिए अलग-अलग जगह से तरह-तरह के लोगों की भीड़ आकर इकट्ठा हो गयी है जो नहा-धो कर वापस अपने घरों को चले जायेंगे या जैसे होटल में कुछ लोग किसी पार्टी में इकट्ठा हुए हों। पर घर व होटल में अन्तर होता है। घर में सभी के मध्य एकात्मकता होती है जो हमारे दल में है, पर बहुगुणाजी का तो होटल है।" इसी प्रकार सत्यप्रकाश मालवीय का कहना था," भारत के नक्शे में उ०प्र० न केवल भौगोलिक धनुष जैसा है, जिसका एक सिरा हरियाणा और दूसरा बिहार को छूता है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसकी धनुष जैसी भूमिका रही है। यही लोकदल का सबसे बड़ा आधार-क्षेत्र रहा है और यहीं से सबसे पहले पार्टी टूटी थी। उ०प्र० में हम लोकदल-ब की रीढ़ तोड़ चुके हैं। उन २८ में अब भगदड़ बची है। कुछ ही दिनों में मुलायम सिंह के साथ के काफी विधायक हमारे साथ आ जायेंगे।"

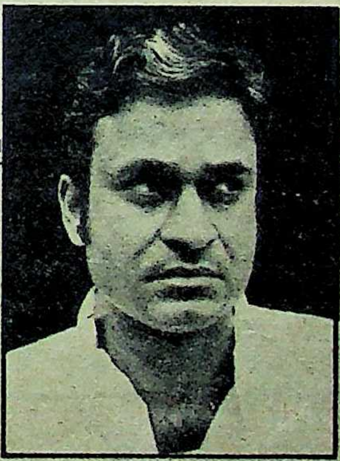

अजय सिंह

अजय सिंह तथा डा० राज सिंह तैलान जैसे मित्र-सलाहकारों, उ०प्र० के ५२ विधायकों तथा विरासत में मिले चौ० चरण सिंह के आधे-अधूरे जनाधार के बल पर ही यदि अजीत सिंह भविष्य पर अपना दावा पेश कर रहें, तो उस पर राजनीतिक समीक्षकों को संदेह होना स्वाभाविक है।

दल की मौजूदा स्थिति के बावजूद इन नेताओं द्वारा 'भविष्य' के प्रति आश्वस्त होने या ऐसा दावा करने के पीछे मुख्य तीन तर्क हैं— प्रथम-चौधरी चरण सिंह द्वारा हिन्दी क्षेत्र में बनाये गये पिछड़ी जातियों व किसानों का जनाधार अभी भी टूटा नहीं है और वह राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेता के रूप में अजीत सिंह के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं करेगा। इस संदर्भ में उनका मानना है कि यह जनाधार न तो बहुगुणा को अपना राष्ट्रीय नेता मानने को तैयार होगा और न ही चन्द्रशेखर को। भाजपा भी इसे तोड़ने में सफल नहीं हो सकती। बहुगुणा के अलावा लोकदल-ब के शेष नेता चाहे वह देवीलाल हों, कर्पूरी ठाकुर हों, मुलायम सिंह या नाथूराम मिर्धा, इनमें किसी का भी प्रभाव अपने प्रदेश की सीमा के बाहर नहीं है और न ही इन्हें हिन्दी भाषी क्षेत्र की पिछड़ी जातियां व किसान अपने राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार करेंगे।

अजीत सिंह के भविष्य के प्रति आश्वस्त होने के पक्ष में जो दूसरा तर्क दिया जातां है वह है—लोकदल-ब में टूट की संभावना। हरियाणा चुनाव में लोकदल-ब की विजय के बाद जहां एक तरफ इस दल का मनोबल व शक्ति बढ़ी है, वहीं राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है कि इस दल की एकता अब ज्यादा दिन बनी रह पाना कठिन है। इस संदर्भ में एक नेता का कहना था— "वहां बहुगुणाजी की स्थिति भारत के राष्ट्रपति से भी कमजोर है जो सर्वोच्च पद पर रबड़ की मोहर की तरह से बैठा रहता है। फिर वहां एक नहीं, चार-चार प्रधानमंत्री हैं।

इन दो तर्कों के अतिरिक्त दिया जाने वाला तीसरा प्रमुख तर्क, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है— "राष्ट्रीय राजनीति में न केवल सत्तारूढ़, बल्कि विपक्षी दलों के मध्य भी शक्ति संतुलन का विचित्र समीकरण। फिलहाल लोकदल-अ के भविष्य को कुछ दूर तक प्रशस्त रखने में यह एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। अजीत सिंह-समर्थकों द्वारा उ०प्र० में मुलायम सिंह का तख्ता पलट देने के बाद डूबते हुए मुलायम सिंह यादव को जनता पार्टी द्वारा समर्थन देकर मजबूत रखना तथा हरियाणा की हार के बाद हड़बड़ाये अजीत सिंह-समर्थकों का मनोबल बनाये रखने के लिये अब चन्द्रशेखर-समर्थकों द्वारा मुलायम सिंह के क्रांतिकारी मोर्चे से अलग होने तथा अजीत सिंह के लोकदल को साथ लेने की कोशिशें, उसी शक्ति संतुलन के राजनीतिक अंकगणित का हिस्सा हैं।

मोर्चा : हरियाणा में जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर, साथ-साथ पराजित होने के बाद अब अजीत सिंह ने लोकदल-ब के विरुद्ध अगला मोर्चा उ०प्र० की जमीन पर लड़ना तय किया है। उस रणनीति में उनकी पहली कोशिश है कि जनता पार्टी मुलायम सिंह द्वारा बनाये क्रांतिकारी मोर्चे से अपना समर्थन वापस ले, ताकि मुलायम सिंह यादव को प्रभावहीन किया जा सके। इस संदर्भ में उ०प्र० जनता पार्टी के ही एक वर्ग द्वारा मुलायम सिंह का खुला विरोध शुरू कर देने व मोर्चे से अलग होने से अजीत सिंह का काम आसान कर दिया

साक्षात्कार/अजीत सिंह

भविष्य तो हमारा ही है

लोकदल-अ के अध्यक्ष अजीत सिंह से हरियाणा में हार के बाद उनकी पार्टी के भविष्य के संदर्भ में पुनीत टंडन की बातचीत के अंश:

माया: हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद अब आप अपने व अपने दल के राजनीतिक भविष्य के विषय में क्या सोचते हैं?

अजीत सिंह: भविष्य तो हमारा ही है। यह बात तो मैं आज कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले से यही बात खुद बहुगुणाजी, देवीलालजी और कर्पूरीजी वगैरह कहते रहे हैं। जब ये लोग मुझे राजनीति में लाये थे और उसके बाद तक भी ये सब नेता मुझसे कहा करते थे कि—हमारी राजनीति तो बस दो-चार वर्षों की है, हम बीते हुए समय के लोग हैं, आगे तुम्हें ही संभालना है, भविष्य तो तुम्हारा ही है।...तो कल तक जो बात ये लोग कह रहे थे, उनकी ही बात को आज मैं भी कह रहा हूं कि भविष्य तो हमारा ही है।

माया: हरियाणा चुनाव में इतनी जबरदस्त शिकस्त खाने के बाद भी इस आत्मविश्वास का आधार क्या है? क्या सिर्फ इसी तर्क के सहारे कि चूंकि कल तक वे सब नेता भी यह कहते थे कि भविष्य आपका ही है, अतः आज आप भी यही मान रहे हैं और कह रहे हैं?

सिंह: हरियाणा चुनाव परिणामों से हम हतोत्साहित नहीं हुए हैं और न ही उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित होगा। वहां एक अलग स्थिति थी। हरियाणा में एक तेज लहर थी जो संयुक्त हरियाणा संघर्ष समिति के आंदोलन के कारण पैदा हुई थी। इस आंदोलन में हम सभी शामिल थे। हम सबने मिलकर इसे मजबूत किया था तथा देवीलालजी को इसका नेतृत्व सौंपा हुआ था। लेकिन देवीलालजी ने पार्टी की टूट के दौरान जो भूमिका अदा की और जिस तरह अंतिम समय में वह पार्टी तोड़ने वालों के साथ जाकर मिल गये, उससे एक जटिल स्थिति पैदा हो गयी। हरियाणा में लोग उनके इस काम से खुश नहीं थे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो सामने थी कि वह किसी भी हालत में कांग्रेस को हटाना चाहते थे। दूसरे पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण हमें हरियाणा में लोगों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। हमारा चुनाव-प्रचार मतदान के सिर्फ सात दिन पहले शुरू हुआ। इस बीच देवीलालजी व उनके समर्थकों ने वहां तमाम ऊलजलूल अफवाहें फैला दीं। इसके बावजूद जहां-जहां मेरी मीटिंग हुई, भारी संख्या में लोग सुनने आये। महम तक में, जो कि देवीलालजी का गढ़ है, भारी तादात में लोग आते थे। वे कहते थे—"आप की बात सही है, देवीलालजी ने गलत काम किया है, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है।" उन्हें डर था कि यदि वोट आपस में बंट गये, तो कहीं कांग्रेस न जीत जाये, जो वह कतई नहीं चाहते थे। अतः लोगों ने, जो हमारे साथ थे, न चाहते हुए भी देवीलालजी के उम्मीदवारों को वोट दिये। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें थीं। जैसे बूथ कैप्चरिंग भी हुई, तमाम जगह देवीलालजी के आदमियों ने पोलिंग बूथ्स पर कब्जा कर अपने खिलाफ लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया। बेहद घृणित स्तर की झूठी अफवाहें, गंदी-गंदी बातें फैलायी गयीं।

रोहतक में देवीलालजी के उम्मीदवार हरद्वारी लाल ने अपने नाम से बड़े-बड़े पोस्टरों में क्या छपवा कर शहर भर में चिपकाया था कि पिताजी (चौ० चरण सिंह) की मैंने और माताजी ने मिल कर हत्या की है। ...कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस कदर गंदे व घिनौने स्तर पर उतर कर ये लोग इतना झूठा व अमानवीय कुप्रचार करेंगे। उसी तरह देवीलालजी ने राष्ट्रीय प्रेस के सामने दिल्ली में खुद कहा कि मुझे कांग्रेस से दो करोड़ रुपए मिले हैं।

माया: जैसे?

सिंह: आप भी तो चुनाव के समय हरियाणा का दौरा कर रहे थे। क्या आपको नहीं मालूम? रोहतक में देवीलालजी के उम्मीदवार हरद्वारीलाल ने अपने नाम से बड़े-बड़े पोस्टरों में क्या छपवा कर शहर भर में चिपकाया था कि पिताजी (चौ०चरण सिंह) की मैंने और माताजी ने मिलकर हत्या की है।...कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस कदर गंदे व घिनौने स्तर पर उतर कर ये लोग इतना झूठा व अमानवीय कुप्रचार करेंगे। उसी तरह देवीलालजी नें राष्ट्रीय प्रेस के सामने दिल्ली में खुद कहा कि मुझे कांग्रेस से दो करोड़ रुपये मिले हैं।

माया: लेकिन उस प्रेस कांफ्रेंस के बाद तो आप व देवीलालजी मिले थे। तब आपने देवीलालजी से इस विषय में क्यों नहीं कहा?

सिंह: कहा। यह बयान जारी करने के बाद भी वह हमसे मिले थे। उस समय अंतिम कोशिश हुई थी समझौते की। मैंने कहा कि चौधरी साहब आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं, आपने ये दो करोड़ रुपए की झूठी बात क्यों उड़ा दी तो हंसने लगे। खुद उन्होंने मुझसे कहा—राजनीति में तो सब चलता है और फिर हरियाणा, वहां तो मैं झूठ को भी सच बना दूं तो वह सच बनकर ही दौड़ेगा। फिर देवीलालजी ने कोई एक झूठ बोला है? सैकड़ों बोले होंगे। तो ठीक है, वह तो देवीलालजी का हरियाणा है, जहां यह झूठ चल गये, लेकिन पूरे देश भर में तो आप झूठ नहीं चला सकते। फिर हरियाणा में भी यह झूठ ज्यादा समय तक नहीं चल सकता।

माया: लेकिन यह तो सच है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकदल के चुनाव चिन्ह के विषय में निर्णय दिये जाने के एक दिन

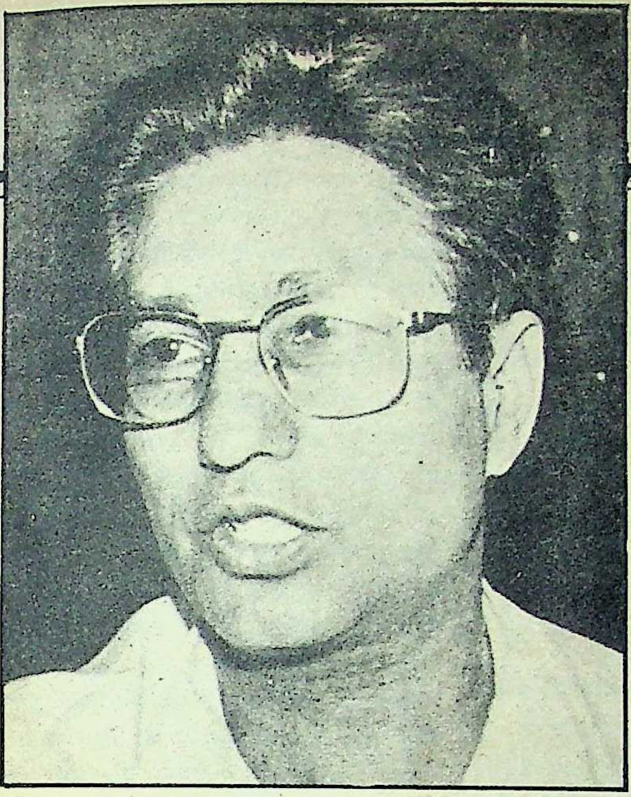

इस एक साल की राजनीति में क्या-क्या नहीं देखा और जाना। कभी सोचा भी नहीं था। जब तक राजनीति में नहीं आया था, तब तक सिर्फ दूर से सुना था कि राजनीति में गंदगी होती है। पर इतनी ज्यादा गंदगी, झूठ और बेईमानी होती है, यह मुझे अब पता चला है। पहले मालूम नहीं था कि इतने बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता भी इतने झूठ और गंदगी पर उतर सकते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि बहुगुणाजी या देवीलालजी इस निचले स्तर की भाषा पर उतर आयेंगे।

'पहले देवीलालजी से आप की मुलाकात हुई थी, पर आप समझौते के लिए तैयार नहीं हुए?

सिंह: यह सच है कि मेरी देवीलालजी से मुलाकात हुई थी, लेकिन देवीलाल जी खुद समझौता नहीं करना चाहते थे।

माया: तो वह आप से मिले क्यों?

सिंह: सिर्फ एक कन्फ्यूजन (भ्रम) बनाये रखने के लिए और लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह तो समझौता चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता। ताकि यह सिद्ध कर वह यह प्रचार कर सकें कि मैं कांग्रेस से मिला हुआ हूं।

माया: क्या अपनी इस बात के पक्ष में कोई प्रमाण दे सकते हैं?

सिंह: हां। अपनी अंतिम मुलाकात के दौरान देवीलालजी से जहां बातचीत खतम हुई थी, वह यह थी कि अभी वार्ता जारी रहेगी तथा हम लोग दुबारा मिल कर अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। तभी यह तय हुआ कि इस बैठक की बात कोई भी पक्ष बाहर नहीं कहेगा तथा इसे गोपनीय रखा जायेगा। इसके तुरंत बाद देवीलालजी ने बल्लभगढ़ में जाकर सबसे कह दिया कि उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी तथा मैं समझौता नहीं करना चाहता। उसके बाद वह दुबारा मिले भी नहीं। इसी तरह महम में लोगों ने हमें बताया कि देवीलालजी ने वहां सब जगह जाकर यह कहा हुआ था कि मैं तो दिल्ली में अजीत के घर सात बार गया, पर वह मिला तक नहीं। जबकि वह यहां एक बार भी नहीं आये।

माया: आपको राज्यसभा में आये एक वर्ष हो गया। उच्च सदन में आपने अब तक न तो एक शब्द बोला है और न ही कोई प्रश्न पूछा है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एक सांसद के रूप में आप अपनी भूमिका अदा करने में असफल रहे हैं?

सिंह: मैं तो अधिकांश समय यहां था ही नहीं। फिर मौका भी नहीं मिला। जबसे पार्टी में आया हूं, दल के आपसी झगड़ों से ही फुरसत नहीं मिल पा रही है। फरवरी तक तो वही सब चलता रहा। उसके बाद दल के संगठनात्मक ढांचे को नये सिरे से मजबूत करने का काम सामने था। उसी में जुटा हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण काम है।

माया: एक साल के राजनीतिक जीवन में आप की क्या उपलब्धि रही-सिर्फ लोकदल की टूट? या इस दौरान आपने कोई जनआन्दोलन खड़ा करने की कोशिश की, कोई संघर्ष किया या चौ०साहब द्वारा छोड़े गये जनाधार का विस्तार किया?

सिंह: जहां तक लोकदल की टूट की बात है, तो यह सच है कि मेरे लोकदल में आने के छह महीने बाद ही पार्टी टूट गयी। लेकिन यह टूट तो बहुत पहले से ही होनी थी। देवीलालजी शुरू से मन बनाये बैठे थे। उन्हें तो बस सही मौके की तलाश थी। फिर यह पहली बार तो हुआ नहीं था। पिताजी के सामने भी पार्टी टूटी थी और इन्हीं लोगों ने—देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर वगैरह ने तोड़ी थी। जहां तक आन्दोलन व संघर्ष की बात है, हम उसकी तैयारी में लगे हैं। मैं मेरठ से लखनऊ की पद-यात्रा करने जा रहा हूं। उसके बाद लखनऊ से पटना तक यात्रा करने की योजना है। इसी के साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत कर जनाधार को और व्यापक बनाने की कोशिश में हम जुटे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है।

माया: क्या सफलता मिली है?

सिंह: अभी राम नरेश यादवजी को हम अपने साथ लाये हैं। समता पार्टी के हमारे साथ विलय से उ०प्र० तथा बिहार में हमारी शक्ति का विस्तार हुआ है। राजेन्द्र सिंहजी जो उ०प्र० में हमारे वरिष्ठ नेता थे और जिन्हें बहुगुणाजी ने निकाल दिया था, वह भी अब हमारे साथ सक्रिय हो रहे हैं। इसी प्रकार पिताजी के साथ के तमाम वरिष्ठ सहयोगी हमारा साथ देने आ रहे हैं।

माया: किंतु हरियाणा की हार से क्या आपके साथियों का मनोबल टूटा नहीं है?

सिंह: नहीं। हरियाणा के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर हरियाणा छोटा-सा राज्य है, जबकि उ०प्र० तथा बिहार की न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां भी हरियाणा के मुकाबले ज्यादा विविध तथा जटिल हैं। उ०प्र० में हमारे साथ ५४ विधायक हैं। उ०प्र० के हर एक विधायक के वोट की कीमत (राष्ट्रपति चुनाव में) हरियाणा के चार विधायक के बराबर है। फिर जिस तरह रोहतक में माताजी के विरुद्ध गंदी-गंदी बातें फैलायी गयीं, पश्चिमी उ०प्र० में उसकी भारी प्रतिक्रिया हुई है। फिर बहुगुणाजी को कोई भी लोकदल का कार्यकर्ता अपना नेता मानने को तैयार नहीं होगा। उनकी पार्टी जितने दिन चल जाये और जितने दिन वह अध्यक्ष रह जायें, वही बहुत है।

माया: अपने एक वर्ष के राजनीतिक जीवन में आपने क्या सीखा?

सिंह: (हंसते हुए) जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीखा था। इस एक साल की राजनीति में क्या-क्या नहीं देखा और जाना! कभी सोचा भी नहीं था। जब तक राजनीति में नहीं आया था, तब तक सिर्फ दूर से सुना था कि राजनीति में गंदगी होती है। पर इतनी ज्यादा गंदगी, झूठ और बेईमानी होती है, यह मुझे अब पता चला है। पहले मालूम नहीं था कि इतने बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता भी इतना झूठ और गंदगी पर उतर सकते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि बहुगुणाजी या देवीलालजी इस निचले स्तर की भाषा पर उतर आयेंगे।

माया: जैसे?

सिंह: अरे, विपक्षी दलों की बैठक के मामले में बहुगुणाजी ने हमारे लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था?

माया: क्या?

सिंह: वो क्या एक शब्द है गन्दा सा (इस बीच बगल में बैठे एक नेता बताते हैं—कुजात) हां—उन्होंने हमें 'कुजात' कहा था। हम 'कुजात' हैं? आप जानते हैं इसका अर्थ। और यह बात बहुगुणाजी जैसा व्यक्ति कहेगा? इसी तरह देवीलालजी ने कितना कुछ कहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, पर अब जाना है कि ये सब पुराने दिग्गज नेता देवीलालजी, बहुगुणाजी, वगैरह किसी भी हद तक उतर सकते हैं।

माया: कहा जाता है कि आप को कांग्रेस से लगातार मदद मिलती रही है और आप का भविष्य कांग्रेस है?

सिंह: इस तरह की बेहूदी अफवाहों में कोई दम नहीं है। यह बिलकुल झूठा प्रचार है।

■ छाया: गिरीश श्रीवास्तव

है। वहीं जनता पार्टी में शुरू में मुलायम सिंह को समर्थन देने की पुरजोर वकालत करने वाले जनता नेता सुधीन्द्र भदौरिया तक अब चन्द्रशेखर को यह राय देने लगे हैं कि केवल मुलायम सिंह यादव को समर्थन देना तथा अजीत सिंह गुट से अलग रहना, पार्टी के दीर्घकालीन हितों के विरुद्ध है। इस बीच अजीत सिंह द्वारा दिल्ली में चन्द्रशेखर से की गयी लगातार कई मुलाकातों में दोनों पक्षों के मध्य प्रगाढ़ता बढ़ी है। अजीत सिंह का कहना है कि जनता पार्टी से हमारे द्वारा किया गया समझौता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं था, यह राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था तथा पूरे देश में शीघ्र ही लागू होगा।

जनता नेताओं द्वारा अब यह खुले आम कहना शुरू हो गया है कि उ०प्र० में क्रांतिकारी मोर्चा बनाते समय मुलायम सिंह ने वायदा किया था कि वह भविष्य में जनता पार्टी में शामिल हो जायेंगे। अब या तो वह उसे पूरा करें अन्यथा जनता पार्टी उनसे समर्थन वापस ले लेगी। क्रांतिकारी मोर्चे के टूटने से जहां एक तरफ मुलायम सिंह की शक्ति को और चोट पहुंचेगी, वहीं यह लोकदल-अ उ०प्र० में दूसरी विजय होगी। यद्यपि इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने भी चन्द्रशेखर से दिल्ली आकर कई मुलाकातें की हैं। इसके बावजूद वह यह आश्वासन पाने में असफल रहे कि जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन जारी रखेगी तथा उ०प्र० में अजीत सिंह गुट अलग-थलग रखा जायेगा।

वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह गुट उ०प्र० में भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव की समता पार्टी का अपने दल में विलय कर अपनी शक्ति का और ज्यादा विस्तार करने में सफल हुआ है। मध्य-पूर्व उ०प्र० के यादवों में जहां रामनरेश यादव के आने से अजीत सिंह का प्रभाव और मजबूत हुआ है, वहीं मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व को भी संकट पैदा हो गया है। लोकदल के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह के पुनः अजीत सिंह के साथ सक्रिय हो जाने से पश्चिमी उ०प्र० के आगरा-अलीगढ़ मंडलों में भी अजीत सिंह का वर्चस्व मजबूत हुआ है।

निश्चय ही यदि अजीत सिंह उ०प्र० में अपनी शक्ति संगठित करने में सफल हो जाते हैं, तो हरियाणा चुनाव के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर लगने वाले प्रश्नचिन्ह हट सकते हैं। अजीत सिंह द्वारा मेरठ से लखनऊ तथा उसके बाद लखनऊ से पटना की प्रस्तावित पदयात्राओं की प्रतिक्रिया उनके भविष्य की दिशा को और ज्यादा स्पष्ट कर देगी।

उ०प्र० के अतिरिक्त अजीत सिंह बिहार तथा राजस्थान में भी अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजस्थान में बुजुर्ग किसान नेता दौलतराम सारण उनके साथ हैं। राजस्थान के किसानों के मध्य अपनी यूनियन बनाकर एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे दौलतराम सारण की नेतृत्व-क्षमता का अजीत सिंह कितना उपयोग कर पायेंगे, इससे पता चलेगा कि उनके दल का राजस्थान में क्या भविष्य होगा। फिलहाल नाथूराम मिर्धा से अपनी कट्टर नाराजगी के कारण सारण अजीत सिंह के साथ हैं। सारण के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि सारण राजस्थान के मामलों में यहां पर भी सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि लोकदल-अ के राजस्थान संबंधी मामलों में अजीत सिंह अभी भी अपने मित्र व भरतपुर के विधायक यदुनाथ सिंह की सलाह पर ही ज्यादा काम करते हैं।

सुधीर गोयल

> "भाई साहब (अजीत सिंह) की कोई भी राजनीतिक समझदारी नहीं है। मैं दावा करता हूं कि राजनीतिशास्त्र का अ ब स पढ़ना तो दूर रहा, उन्होंने अभी तक चौ० साहब द्वारा लिखी गयी पुस्तकें भी नहीं पढ़ीं।"

रामविलास पासवान से दोस्ती : बिहार में अजीत सिंह का भविष्य वहां की विपक्षी राजनीति में कर्पूरी ठाकुर से नाराज नेताओं की नकारात्मक शक्ति पर आधारित है। जातिवाद से आकंठ डूबी बिहार की राजनीति में यादव लाबी की पिछले वर्षों से कर्पूरी ठाकुर से बढ़ती दूरी ही अजीत सिंह की शक्ति का स्रोत है। जिसका नेतृत्व फिलहाल मुंशीलाल राय कर रहे थे। बिहार प्रदेश युवा लोकदल के अध्यक्ष जय प्रकाश यादव के माध्यम से अजीत सिंह युवा लोकदलीय कार्यकर्ताओं को तो अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हुए हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में यहां भी उनका भविष्य कर्पूरी ठाकुर से नाराज लोगों और चन्द्रशेखर की जनता पार्टी के समर्थन पर ही टिका हुआ है। कभी लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव रहने वाले तथा बिहार के प्रभावशाली हरिजन नेता रामविलास पासवान (जो अब जनता पार्टी में हैं) से अजीत सिंह ने अपने संबंध काफी बेहतर कर लिए हैं। बताया जाता है कि रामविलास पासवान दिल्ली की राजनीति कुछ महीने छोड़कर पटना में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ताकि वह अपने कट्टर राजनीतिक शत्रु कर्पूरी ठाकुर से एक बार जमकर दो-दो हाथ कर लें। इसी समय अजीत सिंह भी बिहार में लोकदल-ब के विरुद्ध अपनी मुहिम तेज करेंगे।

वैसे तो अजीत सिंह हरियाणा की हार के बावजूद वहां भी आशा लगाये बैठे हैं। उन्हें आशा है कि देवीलाल की सरकार के छह महीने पूरे होते होते हरियाणा में एक बार फिर वह अपनी जड़ें मजबूत करने में सफल हो जायेंगे, क्योंकि तब तक हरियाणवी जनता का इस सरकार से मोहभंग हो चुका होगा।

निश्चय ही अजीत सिंह की इन कोशिशों और योजनाओं को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि उनकी राजनीति की शुरुआत के साथ ही उसका अंत शुरू हो गया है। लेकिन भविष्य में अजीत सिंह अपनी इन योजनाओं को कहां तक सफल कर पायेंगे तथा अपने दल को कितना मजबूत बना पायेंगे, यह कहना भी कठिन है। उनके दल के अंदर ही मौजूद अंतर्विरोध अभी उभर कर सामने नहीं आया है, लेकिन अपनी दक्षिणपंथी तथा अमरीकी-समर्थक नीतियों के लिए मशहूर सुब्रह्मण्यम स्वामी समाजवादी नेता सत्यप्रकाश मालवीय से कब तक पटरी बिठाये रख पायेंगे, कहना कठिन है। सुब्रह्मण्यम स्वामी का खुद 'माया' से मानना था, "मैं केन्द्र से दायीं तरफ हूं तथा मालवीयजी केन्द्र से बायीं तरफ हैं। हम दोनों ही लोकदल की नीतियों को मानते हैं।" लोकदल की नीतियां केन्द्र से दायीं तरफ हैं या बायीं तरफ हैं, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इसके जवाब में सुब्रह्मण्यम स्वामी का कहना था कि यह आप खुद तय करें, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये चौधरी साहब की नीतियां हैं और चौधरी साहब गांधी तथा पटेल की नीतियों के समर्थक थे तथा नेहरू के विरोधी। इस दौरान अजीत सिंह द्वारा भी समय-समय पर दिये वक्तव्यों में एक भटकाव अवश्य नजर आता है। कभी अपने पुराने अमरीकी अनुभवों तथा सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रभाव में वह ठेठ अमरीकी समर्थक तथा वामपंथ विरोधी बयान दे देते हैं, तो कभी सत्यप्रकाश मालवीय द्वारा तैयार किये गये समाजवादी भाषा के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर देते हैं। निश्चय ही अजीत सिंह राजनीतिक दर्शन के बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हैं और राजनीतिक शब्दावलियां अभी भी उनके लिए अपरिचित हैं। कभी उनके बहुत निकट रहने वाले तथा उनके अनौपचारिक राष्ट्रीय प्रचार सचिव सुधीर गोयल का कहना है "भाई साहब (अजीत सिंह) की कोई भी राजनीतिक समझदारी नहीं है। मैं दावा करता हूं कि राजनीतिशास्त्र का अ ब स पढ़ना तो दूर रहा, उन्होंने अभी तक चौ० साहब द्वारा लिखी गयी पुस्तकें भी नहीं पढ़ीं। वह सिर्फ राजीव गांधी की शैली में अपने विदेश से लौटे कुछ दोस्तों की गैरराजनीतिक सलाहों-मशविरों पर गलत-सलत कदम उठाते रहे हैं।" अजीत सिंह को छोड़कर कुछ ही दिनों पहले लोकदल (बहुगुणा) में शामिल हुए अजीत सिंह के यह प्रचार सचिव अब अजीत सिंह विरोधी प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि अजीत सिंह राजनीतिक रूप से निरक्षर हैं। यदि सुधीर गोयल के अनुभवों में कुछ सच्चाई है, जो कि अजीत सिंह के साक्षात्कारों व भाषणों से भी स्पष्ट है, तो यह मानना होगा कि जहां एक तरफ अजीत सिंह को अपना भविष्य बनाने के लिए अपने अंग्रेजीदां मित्रों से अलग होकर चौ० साहब द्वारा छोड़ी गयी चौपालों पर बैठना होगा, वहीं राजनीतिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों के अतिरिक्त भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक व जातीय ढांचे के ताने-बाने की सही समझ भी विकसित करनी होगी, जो कि उनके पिता चौधरी चरण सिंह की विशिष्टता थी। उस विशिष्टता के बिना उनके द्वारा छोड़ी गयी विरासत को संभाल पाना न केवल मुश्किल बल्कि असंभव कार्य है। वह तब, जब वह सत्ता की नहीं विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं।

—पुनीत टण्डन

जीत का स्वागत : चुनाव-परिणाम की घोषणा के बाद वेंकटरमण का पारंपरिक स्वागत

आर० वेंकटरमण

कैसे राष्ट्रपति सिद्ध होंगे ?

राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में ऐसा कोई राजनीतिक धमाका नहीं हुआ, जिसकी संभावनाएं आखिरी क्षणों तक व्यक्त की जा रही थीं। लेकिन आर० वेंकटरमण ऐसे समय राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहे हैं, जब ज्ञानी जैल सिंह ने अपने आखिरी समय में राष्ट्रपति की भूमिका को काफी विवादास्पद बना दिया है। राजीव गांधी के लिए यह राष्ट्रपति चुनाव काफी महत्वपूर्ण था। उनकी नौका इस समय भंवर में है। उन्हें ऐसा राष्ट्रपति चाहिए, जो ज्ञानी जैल सिंह की तरह उनकी नींद हराम न करे। लेकिन नियमों के पाबंद और पचास साल के राजनीतिक अनुभव से लैस आर० वेंकटरमण क्या राजीव गांधी की हां-में-हां मिलाने वाले राष्ट्रपति सिद्ध होंगे ?

वह एक प्रौढ़ राजनेता हैं। वह उन अग्रणी नेताओं में से भी हैं, जिन्होंने आजाद भारत की राजनीति को आकार दिया है। पिछले पचास सालों में उनकी अपनी पार्टी ने जो करवटें ली हैं, उसके भी वह साक्षी रहे हैं। लेकिन रामास्वामी वेंकटरमण जिस समय राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय वह इस बात से नावाकिफ नहीं हैं कि उन्होंने जिस पार्टी को अलविदा कहा है, उसमें तूफान मचा है और उनको जो विरासत मिली है; वह निरापद नहीं है। इसके बावजूद वह कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मेरे सामने कोई समस्या नहीं आयेगी।"

टेढा मार्ग : उनके कुछ भूतपूर्व साथियों को उनकी इस आशावादिता में अहंकार की बू आ सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनमें वह बूता है, जिसकी बदौलत वह अपने पूर्वाधिकारी द्वारा कुरेदे गये विवाद का सामना कर सकते हैं। यह विवाद है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को लेकर—जिसने दो सर्वोच्च पदों की गरिमा को धूमिल किया है। लेकिन यह काम बेहद आसान नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपतीय इतिहास में ऐसा कभी कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ, जैसा ज्ञानी जैल सिंह ने अपने आखिरी दिनों में खड़ा किया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के तनावपूर्ण संबंधों के नतीजों ने वेंकटरमण के रास्ते को काफी रपटीला बना दिया है। यह मामला कितना टेढ़ा है, यह स्वयं उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में देख लिया है। अनुच्छेद-७८ के तहत राष्ट्रपति के सूचना पाने के अधिकार को लेकर उच्च सदन में छिड़ी गर्मागर्म बहस को उन्होंने झेला है। लोकसभा-अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने राष्ट्रपति के संबंध में किसी भी तरह की अनुमति न देकर सरकार और

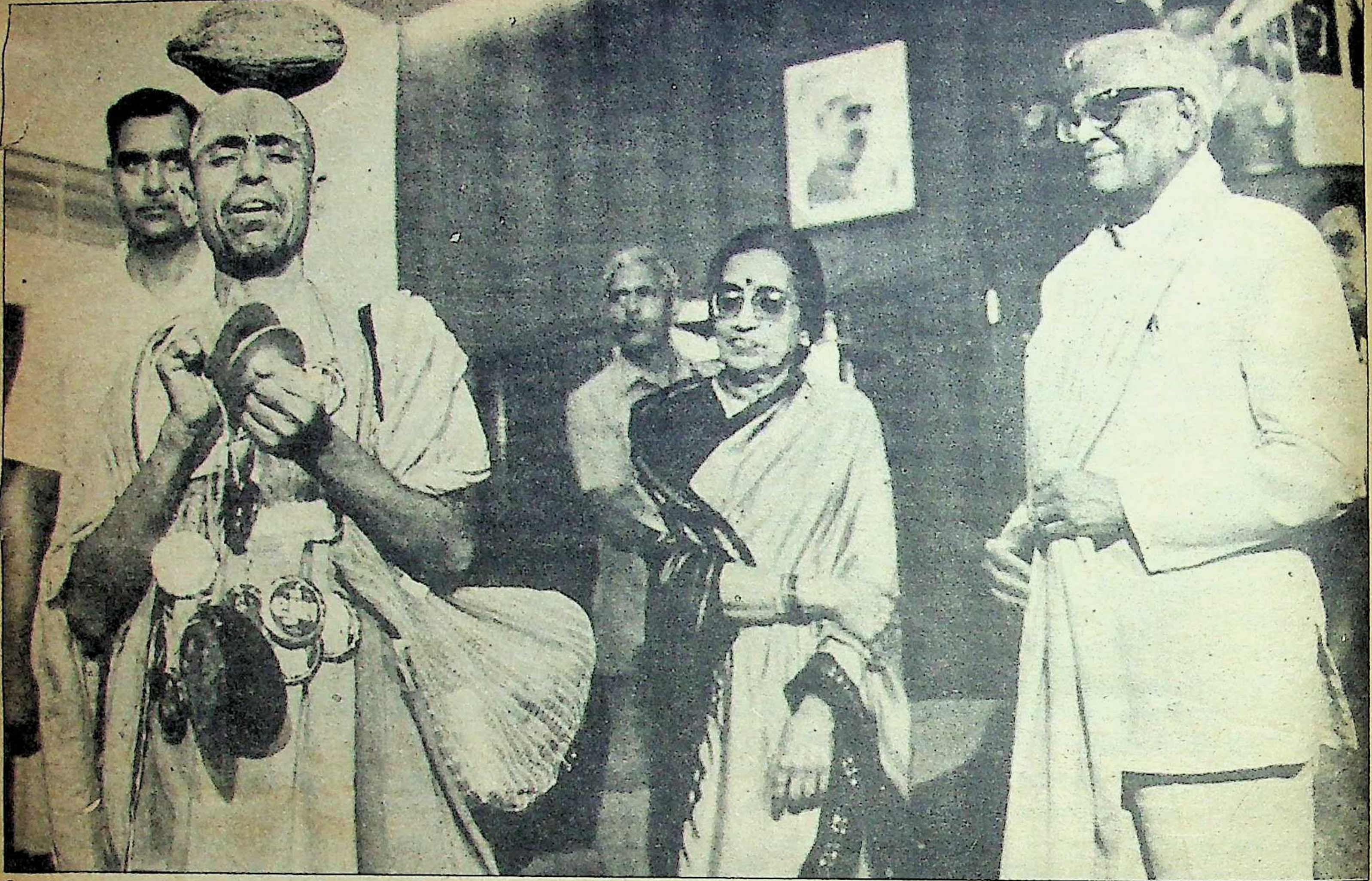

विजयोल्लास

खासकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बचाव कर लिया था। लेकिन वेंकटरमण ने बहस पर ढक्कन रखने के बजाय ब्रिटिश परम्पराओं पर नजर दौड़ाई। इस झिझक के कारण वह राज्यसभा में इस मसले पर शुरुआती बहस को नहीं रोक पाये। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस झिझक के कारण वह एक प्रकार से राष्ट्रपति बनने का मौका खो चुके थे। प्रधानमंत्री के सलाहकारों को यह बात पसंद नहीं आयी थी कि वह इतनी कानूनी बारीकियों में जायें। कानूनी औचित्य को तरजीह देने की उनकी प्रवृत्ति से सलाहकारों को लगा कि 'रबर मोहर' राष्ट्रपति बनने की उनकी योग्यता संदिग्ध है। जब यह बात वेंकटरमण को पता चली, तो उन्होंने आभास दिया कि यदि उनको टाला गया, तो वह इस्तीफा दे देंगे। संकटग्रस्त राजीव गांधी के लिए यह इस्तीफा और आफत पैदा करता। इसलिए मोहम्मद यूनुस, बी० शंकरानंद, मार्गथम चंद्रशेखर, पी०वी० नरसिम्हाराव, पुपुल जयकर जैसे नामों पर आगे चर्चा करने के बजाय वेंकटरमण को ही उम्मीदवार घोषित करना उनके लिए जरूरी हो गया। यदि वेंकटरमण के इस्तीफे का डर नहीं होता, तो बहुत संभव है कि राष्ट्रपति पद के लिए राजीव गांधी किसी अन्य को उम्मीदवार बनाते।

नाटकीय मोड़ : अजीब बात तो यह है कि बहुत सारे कांग्रेसी और विपक्षी नेता यह मानते हैं कि यदि राजीव गांधी के सामने कोई मजबूरी न होती, तो वह वेंकटरमण के बजाय कृष्णा अय्यर को ही अपना प्रत्याशी बनाते। बताया जाता है कि वस्तुतः अय्यर को कांग्रेसी-प्रत्याशी बनाये जाने की संभावनाओं और चर्चाओं की वजह से ही विपक्ष में दरार पड़ गयी थी और हरियाणा चुनावों की हार से उत्साहित असंतुष्ट कांग्रेसी राष्ट्रपति पद के लिए ज्ञानी जैल सिंह की ओर झुक गये थे। इन लोगों को यह भी भय था कि वामपंथ की ओर रुझान रखने के कारण अय्यर वामपंथी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त करके राजीव गांधी की सरकार का ही पोषण करेंगे और भारत सरकार रूस की झोली में चली जायेगी। राजीव गांधी की हाल की रूस यात्रा से तो दक्षिणपंथी और नरमपंथी नेता चौंक उठे। एक नेता का कहना था, "हम भारत को दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहते।"

लेकिन असंतुष्ट कांग्रेसी और विपक्षी नेता ज्ञानी जैल सिंह से अलग क्यों हुए ? उनके राष्ट्रपति बनने की सारी संभावनाएं समाप्त क्यों हो गयीं ? उक्त नेता के अनुसार, "असंतुष्ट कांग्रेसी जैल सिंह की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के कार्य में बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक बीच में ही उनका धैर्य और मनोबल टूट गया। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें जैल सिंह की विजय में कोई संदेह था, बल्कि उन्हें आशंका थी कि ऐन मौके पर ज्ञानीजी अपनी निष्ठा बदल भी सकते हैं। यद्यपि ज्ञानीजी ने राजीव गांधी को झाड़-पोंछकर बराबर कर दिया था, लेकिन अधिकांश असंतुष्ट कांग्रेसियों के लिए यह बात भूल पाना मुश्किल था कि कुछ ही अर्सा पहले जैल सिंह ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो वह फर्श पर झाड़ू भी लगा सकते हैं। उन्हें भय था कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ज्ञानीजी राजीव गांधी से समझौता कर लेंगे। यही भय था, जिसकी वजह से अधिक विलंब होने के पूर्व ही असंतुष्ट कांग्रेसियों ने ज्ञानीजी से पल्ला झाड़ लिया।

आंध्र प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बन जाने के बाद एन०टी० रामाराव ने भी इसी तरह रंग बदला था। असलियत यह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को विपक्षी दलों और मीडिया के दबाव के कारण रामाराव के सामने झुकना पड़ा था, लेकिन दुबारा सत्ता में आने के बाद रामाराव ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को दूध की मक्खी की तरह त्याग दिया, बल्कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप भी लागू कर दी। इस प्रकार ज्ञानीजी के प्रति आशंकाओं के कारण वेंकटरमण को अंतिम क्षणों में उन असंतुष्ट कांग्रेसियों का भी समर्थन प्राप्त हो गया, जो नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी का यह प्रत्याशी विजयी हो।

इस नाटकीय मोड़ का आलम तो यह था कि शुरू-शुरू में जहां यह कहा जा रहा था कि कांग्रेसी इस चुनाव में पाला बदल कर विपक्षी प्रत्याशी को अपना मत देंगे, वहीं मतदान के ठीक दो दिन पूर्व एक प्रमुख विपक्षी नेता ने दावा किया था कि बहुत से विपक्षी सदस्य पाला बदलकर कांग्रेस-प्रत्याशी वेंकटरमण

11156

को ही वोट देंगे। वेंकटरमण को विजयी बनाने के लिए ये असंतुष्ट कांग्रेसी और विपक्षी नेता इतने उत्सुक थे कि जब यह अफवाह उड़ी कि कुछ दैनिक समाचार पत्र वेंकटरमण के परिवार के संबंध में कुछ नुकसानदेह तथ्य प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो इन नेताओं ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित होने से रोकने के लिए काफी भाग-दौड़ मचायी। इस चुनाव में पक्ष-विपक्ष ने वेंकटरमण को जो एकजुट समर्थन दिया और उनकी योग्यता और निष्ठा के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, वह समस्याओं को सुलझाने और गांधी परिवार के प्रति अपने रुख का निर्धारण करने में नये राष्ट्रपति के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

आशकाए-अपेक्षाए : वफादारों की आम राय है कि वेंकटरमण वृद्ध पुरुष हैं और श्रीमती गांधी के निधन के पहले से ही वह राजीव गांधी के सलाहकार रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ज्ञानी जैल सिंह के समान राजीव सरकार के लिए परेशानी का कारण बन जायेंगे। लेकिन लालकृष्ण अडवाणी जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञों का विश्वास है कि वेंकटरमण 'रबर-स्टैंप' राष्ट्रपति साबित नहीं होंगे। उन्हें भरोसा है कि वेंकटरमण अपने व्यक्तिगत और दलगत संबंधों के बजाय संविधान की अनुशंसाओं और गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने कभी गांधी परिवार के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा का इजहार किया हो, लेकिन उन्होंने कभी ज्ञानीजी की तरह 'झाड़ू तक लगाने' जैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। वेंकटरमण को इतिहास की समझ है और वह उसका आदर करते हैं, जबकि ज्ञानी जैल सिंह एक शातिर राजनीतिज्ञ हैं, जो भविष्य के लिए अपने वर्तमान को अंधकारमय नहीं बनने देता—यही वजह थी कि राजीव गांधी ने जैल सिंह से मिलना तब भी जारी रखा, जब यह निश्चित हो गया कि वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे।

वास्तव में ज्ञानी जैल सिंह से करीबी संबंध बनाकर रखनेवाले कुलदीप नैयर ने ६ और १२ जुलाई के बीच न्यायमूर्ति वाई०वी० चंद्रचूड़ से उन याचिकाओं पर दो बार विचार-विमर्श किया था, जिनमें राष्ट्रपति से राजीव गांधी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गयी है। नैयर के अनुसार न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जैल सिंह को विश्वास दिलाया था कि ऐसी अनुमति देने का उन्हें अधिकार है। दूसरी ओर राम जेठमलानी, जार्ज फर्नांडीस और असंतुष्ट कांग्रेसियों का एक वर्ग प्रत्यक्ष रूप से जैल सिंह पर राजीव गांधी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए अंतिम क्षणों तक दबाव बनाये हुए था। उनकी कोशिश थी कि जैल सिंह उनकी याचिका को स्वीकृत कर दें, जिससे राष्ट्रपति चुनावों के समय राजीव गांधी एक बड़ी परेशानी में पड़ जायें। यद्यपि निजी तौर पर अनेक कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि ज्ञानीजी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल करेंगे।

ज्वलंत मसले : ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति भवन से चले जाने के बाद विपक्ष शांत होकर बैठ जायेगा, इसकी संभावना नहीं है। संसद के अंदर व बाहर वह प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने की याचिका, विचाराधीन पोस्टल बिल और अन्य विवादास्पद मामलों पर हायतौबा मचाता रहेगा और देर-सबेर नये राष्ट्रपति को इन मुद्दों पर कोई-न-कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जितनी समस्याओं के साथ वह अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उतनी समस्याएं उनके पूर्व के किसी राष्ट्रपति को विरासत में नहीं मिली थीं। इन सब मसलों को हल करने के साथ-साथ उन्हें अपनी और अपनी सरकार की विश्वसनीयता भी स्थापित करनी होगी।

नये राष्ट्रपति वेंकटरमण ने इन पंक्तियों के लिखे जाने तक अपने भावी कार्यक्रमों के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है, सिवाय इसके कि वह अपने पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा स्थापित स्वस्थ परंपराओं का पालन करेंगे। डा० राजेंद्र प्रसाद, डा० एस० राधाकृष्णन और डा० जाकिर हुसैन के समान ही वेंकटरमण ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रचार नहीं किया। इन सब बातों से प्रेक्षकों को भरोसा है कि संकट की घड़ी में वेंकटरमण सत्य और न्याय का पक्ष लेंगे। इसी भरोसे पर नैतिकता को मुख्य हथियार बनाकर विपक्ष भी सरकार से अपना संघर्ष जारी रख सकेगा।

नये राष्ट्रपति वेंकटरमण की समस्याएं तथा राजीव गांधी और उनकी सरकार की समस्याएं आपस में इस कदर गुंथी हुई हैं कि न चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे के आमने-सामने आना पड़ेगा। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि संसद का यह मानसून सत्र बड़ा हंगामेदार होगा। बजट सत्र में बोफोर्स, फेयरफैक्स जैसे अनेक हंगामी मामले तो मानसून सत्र को गरम रखेंगे ही, साथ ही कुछ नये मामले भी संसद को झकझोर सकते हैं। राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री से पूछे गये धाराप्रवाह सवालों में ऐसे कुछ मामलों की ओर संकेत किया है। नये राष्ट्रपति परेशानी में डालने वाले इन मामलों से बच नहीं पायेंगे। सबसे ज्यादा हंगामा तो संविधान की धारा-७८ की व्याख्या को लेकर मचने की संभावना है।

यद्यपि नये राष्ट्रपति ने अपने विचारों में बड़ा सौम्य और समझौतावादी रुख अपनाया है (देखिए, साक्षात्कार), लेकिन विपक्ष को भरोसा है कि ये सब बातें तो वह आम जनता में अपनी सौम्य छवि स्थापित करने के लिए कह रहे थे, और यदि उन पर दबाव पड़ा तो उनके लहजे और रुख में परिवर्तन भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ऐसी नौबत अब कभी आयेगी। यद्यपि जैल सिंह उनके लिए समस्याओं का जखीरा छोड़ गये हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में राजीव गांधी को अपने सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया था, उसे देखते हुए इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती कि अब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की उपेक्षा करने या उनसे दंभपूर्ण व्यवहार करने का साहस करेगा। बहरहाल, नये राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण के आनेवाले दिन समस्याओं से भरे हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने सही मुद्दों के लिए जो संघर्ष किया, उससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए उन्हें ज्ञानी जैल सिंह को धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी रूह अभी काफी लंबे समय तक राष्ट्रपति भवन में मंडराती रहेगी।

—रंजना कक्कड़

अब पार्टी नहीं, संविधान के प्रति समर्पित: वेंकटरमण, तमिलनाडु के राज्यपाल एस०एल० खुराना के साथ

साक्षात्कार/आर० वेंकटरमण

यह कोई नहीं कह सकता कि हर सूचना राष्ट्रपति को देनी ही चाहिए

उनकी ७७ वर्ष की उम्र का अधिकांश समय सत्ता के सुख और वैभव में कटा है। यद्यपि राष्ट्रपति का पद काफी संतोषदायी और उनके लंबे राजनीतिक जीवन का समुचित शिखर बिंदु है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको यह अति उल्लसित कर सके। जब रंजना कक्कड़ उनसे उनके ६, मौलाना आजाद रोड स्थित आवास पर मिलीं, तो उस समय आर० वेंकटरमण उप राष्ट्रपति के पद पर ही थे। लेकिन राष्ट्रपति-निवास में वह कुछ समय बाद ही प्रवेश करने वाले थे। इसलिए उन्होंने बजाय 'उपराष्ट्रपति' के विचार जानने के, 'राष्ट्रपति' के ही विचार जानने की कोशिश की है। हालांकि ज्यादातर मुद्दों पर उन्होंने मितभाषिता से ही काम लिया, लेकिन जिन विषयों पर भी बोले उन पर उन्होंने अपनी साफ-साफ राय जाहिर की। रंजना कक्कड़ के लिए यह प्रसन्नतादायक बात है कि उनको वेंकटरमण से उन विषयों पर बात करने का अवसर मिला, जिन पर राष्ट्रपति बनने के बाद शायद न मिल पाता। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंश :

माया : आपने चुनाव-प्रचार क्यों नहीं किया? क्या आप यह महसूस करते हैं कि ऐसे ऊंचे पद को गरिमा प्रदान करने के लिए तटस्थता और सर्वसम्मति आवश्यक है?

वेंकटरमण : भारत के राष्ट्रपति का पद एक कार्य-निष्पादक राष्ट्रपति का पद नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति की तरह वह नीतियों का निर्माण नहीं करता। यहां एक औपचारिक राष्ट्रपति होता है, इसलिएं वह किस चीज का प्रचार करने जाये? वह जाकर यह नहीं कह सकता कि वह ये नीतियां बनायेगा और इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा। वह राष्ट्राध्यक्ष है और वह सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का। इसलिए इस पद के लिए चुनाव-प्रचार करना इसकी गरिमा को घटाना है।

माया : लेकिन कुछ राष्ट्रपतियों ने चुनाव-प्रचार किया है?

वेंकटरमण : जिन राष्ट्रपतियों ने चुनाव-प्रचार नहीं किया, वे काफी जाने-माने रहे हैं—डा० राधाकृष्णन, डा० जाकिर हुसैन, आदि। अपनी निष्पक्षता और तथ्यपरकता के लिए वे सारे देश में ख्यात रहे हैं।

माया : क्या इस रुख के पीछे यह बात भी रही है कि वी०आर० कृष्णा अय्यर आपके व्यक्तिगत दोस्त हैं?

वेंकटरमण : वह मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चुनाव-प्रचार न करने से इस बात का लेना-देना नहीं।

माया : जैसी कि अफवाह थी, क्या आपको कांग्रेसियों द्वारा प्रतिकूल मतदान की आशंका थी?

वेंकटरमण : नहीं, बिलकुल नहीं। मुझे इस बात की बिलकुल भी शंका नहीं थी कि कांग्रेसी अपने उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी उम्मीदवारी का कांग्रेसी पूरी एकजुटता के साथ समर्थन करेंगे।

माया : रक्षा-सौदों को लेकर आपके खिलाफ कानाफूसी-अभियान चला, लेकिन आप चुपचाप रहे। पनडुब्बी और बोफोर्स सौदों से आपका कोई लेना-देना नहीं था, क्योंकि एक आपके रक्षामंत्री बनने के पहले संपन्न हुआ और दूसरा पद छोड़ने के बाद। इस तथ्य के बावजूद आपने अपनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक क्यों नहीं समझा?

वेंकटरमण : यह ऐसा मसला था, जिसमें एक व्यक्ति की गरिमा जुड़ी हुई थी। आखिर यह कहने से क्या मिलता कि यह काम मैंने नहीं किया, बल्कि मेरी पार्टी ने किया है। यह बात कहना ठीक नहीं है। अगर यह गलत है, तो गलत है—चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे मैंने किया हो या मेरी पार्टी ने। एक सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए कि कोई बात गलत हुई या नहीं और यह किसने की?

माया : क्या कोई गलत काम हुआ?

वेंकटरमण : (हंसकर) मुझे नहीं पता।

माया : राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? संविधान-निर्माताओं ने शुरू में इसकी क्या परिकल्पना की थी?

वेंकटरमण : मैंने राज्यसभा में फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन की बादशाहत की है। राष्ट्रपति को सलाह, मार्गनिर्देश और आगाह करने का अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रपति कई मामलों में सलाह दे सकता है। लेकिन यदि आप कहें कि उसकी सलाह मानी जानी चाहिए, तो फिर यह सलाह नहीं रहती। यह आदेश हो जाता है। यह मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी सलाह स्वीकार होनी ही चाहिए? मेरे ख्याल में राष्ट्रपति की भूमिका सलाह देने और मार्गदर्शन तक है। मैं नहीं समझता कि इससे राष्ट्रपति के पद की गरिमा घटी है। संविधान ने उसको यह भूमिका सौंपी है और संविधान का यही मकसद है। भविष्य में कौन सी समस्याएं सामने आयेंगी, इनकी आप कल्पना नहीं कर सकतीं और फिर कल्पना के सहारे इनका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता।

माया : हाल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों और कुछ खास परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में विवाद उठे हैं। इस उच्च पद की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए क्या आप सोचते हैं कि तत्काल इसकी स्पष्ट व्याख्या हो जानी चाहिए?

वेंकटरमण : यदि ऐसी कोई स्थिति खड़ी होती है, तो मैं तत्काल विधि अधिकारियों और संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह लूंगा और उसके आधार पर कार्य करूंगा। मैं अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकता। राष्ट्रपति को सुयोग्य व्यक्तियों और विधि अधिकारियों से सलाह और परामर्श लेना होता है। मसलन जब कभी भी राजेंद्र प्रसाद और पंडितजी के बीच कोई मतभेद होता था, तो वे महाधिवक्ता की सलाह लेते थे।

माया : इसका मतलब है कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि कोई अस्पष्टता है और किसी तरह के संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता है?

वेंकटरमण : इस समय मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की अस्पष्टता है। अगर कोई ऐसा मौका आयेगा, तो मैं विशेषज्ञों की राय लूंगा।

माया : राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद-७८ और अन्य मुद्दों पर कृष्णा अय्यर ने अपना मत व्यक्त किया है। राज्यसभा में दिये गये फैसले को ध्यान में रखते हुए क्या आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे?

वेंकटरमण : मैं कह चुका हूं कि राष्ट्रपति को मसलों पर राय देने का कार्य सौंपा गया है। इस काम को करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जहां तक प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का संबंध है, यह इस बात पर निर्भर करता

है कि दोनों के रिश्ते कैसे हैं। यदि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति में विश्वास है, तो वह पूरी सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा। यदि राष्ट्रपति में विश्वास नहीं है, तो वह सूचनाएं नहीं भी दे सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति का विश्वास है, तो वह उसको वह सलाह देगा, जिसे देना वह जरूरी समझता है। इसलिए यह रिश्ता पूरी तरह आपसी विश्वास और भरोसे पर टिका हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री को हर सूचना राष्ट्रपति को देनी ही चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति रोजाना दस सवाल भेजता है कि कन्याकुमारी में यह क्या हुआ, कश्मीर में वह क्या हुआ, बंगाल और गुजरात में यह क्या हुआ और इसी तरह के अन्य सवाल, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या कर सकता है। राष्ट्रपति के पास काफी समय है। इसलिए यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी कानूनी व्याख्या की जा सके। यह सब कुछ पारस्परिक भरोसे और विश्वास पर निर्भर है।

माया : क्या किन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बरखास्त कर सकता है?

वेंकटरमण : मैं काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं देता। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने कभी काल्पनिक संवाल पूछने की अनुमति नहीं दी और उसी अधिकार का आपके संदर्भ में भी इस्तेमाल करूंगा।

माया : एक आदर्श राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए?

वेंकटरमण : एक आदर्श राष्ट्रपति वह है जो देश में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना पैदा कर सके। वह शांति और विकास का वातावरण पैदा करने में सक्षम हो। उसके पास कार्यकारी अधिकार नहीं हैं।

माया : राष्ट्रपति के रूप में आपके सरोकार क्या होंगे?

वेंकटरमण : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मेरी रुचि सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में होगी। समाज के विभिन्न तबकों में आपसी विश्वास का निर्माण करना, इस समय आवश्यक प्रतीत होता है।

माया : इस समय देश में हिंसा का वातावरण है। क्या राष्ट्रपति इस हिंसा पर अंकुश लगाने और मरहमी स्पर्श देने में भूमिका निभा सकता है या उसे निभानी चाहिए?

वेंकटरमण : विभिन्न समुदायों पर वह अपना नैतिक प्रभाव डाल सकता है। उसे ऐसा करना चाहिए; उसको ऐसा मौका देना चाहिए कि विभिन्न समुदायों के लोग उससे मिलें और वह उनमें एक दूसरे को समझने की भावना भरे। नियंत्रण करना और दबाना राष्ट्रपति का काम नहीं है, यह काम सरकार का है।

माया : यदि हिंसा लगातार होती रहे और नियंत्रण से बाहर हो जाये तो क्या आप आंतरिक आपातकाल का अनुमोदन करेंगे।

वेंकटरमण : बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस समय कोई यह बात कैसे कह सकता है। यह फिर काल्पनिक सवाल आप पूछ रही हैं। यह हालत और संविधान की भावना पर निर्भर है।

माया : आपके मामले में राजनीतिक प्रेक्षकों को जो सबसे बड़ी बात परेशान करती है, वह है आपकी उम्र। क्या आप इसे एक बाधा मानते हैं?

वेंकटरमण : यह बात दूसरों के कहने के लिए है। (ठहाका मारकर फिर इसी वाक्य को दुहराते हैं)

माया : भारत के संबंध में आपका कोई सपना है। अगर है, तो क्या?

वेंकटरमण : असलियत तो यह है कि अगर मेरा कोई सपना नहीं होता, तो मैं आजादी की लड़ाई में नहीं कूदता और न जेल जाता। मैं संपन्न, प्रसन्न और सुविकसित भारत देखना चाहता हूं। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि भारत संसार के अग्रणी देशों में हो।

माया : एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी आपने सपना देखा होगा जो आजादी मिल जाने के बाद आंशिक रूप से पूरा हो गया होगा। क्या आजादी के बाद अब वह पूरा हो गया?

वेंकटरमण : मैं कहना चाहूंगा कि वह पूरा होने की प्रक्रिया में है। कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि ४० वर्ष में सपना पूरा हो जाये। आखिर हम २०० सालों से भी ज्यादा समय तक औपनिवेशिक प्रशासन से पीड़ित रहे हैं और उस दौरान हम संसार की अनेक चीजों से वंचित रहे हैं। उदाहरण के लिए हम १८वीं शताब्दी में होने वाले तकनीकी और वैज्ञानिक परिवर्तनों तथा औद्योगिक क्रांति में भाग नहीं ले सके। इसलिए हमें इन क्षेत्रों में शेष दुनिया के बराबर पहुंचना है। हमने पिछले चालीस सालों में जो हासिल किया है, वह काफी उल्लेखनीय हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद आजाद हुए किसी भी देश के साथ आप भारत की तुलना कर सकती हैं। आप पायेंगी कि हमारी उपलब्धियां चमत्कारिक हैं। हमने खाद्य समस्या को सुलझा लिया, हम एक औद्योगिक देश बन गये, विज्ञान और तकनालाजी में हम उन्नत हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे पिछले चालीस साल का कार्य गर्व के योग्य है।

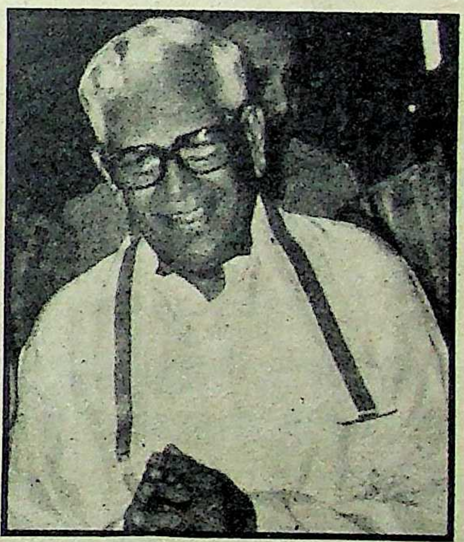

एक आदर्श राष्ट्रपति वह है जो देश में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना पैदा कर सके। वह शांति और विकास का वातावरण पैदा करने में सक्षम हो।

माया : क्या आपने जैसी अपेक्षा की थी, उसके अनुरूप लोकतंत्र फल-फूल रहा है?

वेंकटरमण : हां, बिलकुल। वास्तव में मुझे अपने देश के आम आदमी पर बड़ा भरोसा है। जब भी वे जनादेश देते हैं, वह निर्णायक होता है। उन्होंने कांग्रेस को जनादेश दिया था। जब वे असंतुष्ट हुए, तो १९७७ में विपक्ष को भारी बहुमत से जिता दिया। जब विपक्ष उसका उपयोग नहीं कर पाया, इसे सफल नहीं बना पाया, तो यह भारत के लोगों का दोष नहीं था। जब देखा कि विपक्ष ने जनादेश के अनुकूल अपने को नहीं सिद्ध किया, तो उन्होंने फिर कांग्रेस को जिता दिया। इस प्रकार वे अपने अधिकार का बहुत होशियारी से इस्तेमाल करते हैं।

माया : आम आदमी की स्थिति के बारे में आपकी राय क्या है?

वेंकटरमण : मैं यह नहीं कहूंगा कि उनकी आशाएं पूरी हो गयीं। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि उनकी आकांक्षाएं पूर्णतया अपूर्ण नहीं रही हैं। हमारे भारी विकास को जनसंख्या ने बौना किया है। हमारी अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक वृद्धि हुई है, लेकिन उसको तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने ढक दिया है। पंडितजी से एक बार पूछा गया था कि आपकी समस्याएं क्या हैं? पंडितजी का उत्तर था—"३६ करोड़ समस्याएं।" अगर आप कल राजीव से यही सवाल करेंगी, तो वह कहेंगे ८० करोड़ समस्याएं। आज आप देख रही हैं कि हमारी जनसंख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गयी। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में दूसरी बात यह है कि गरीबी-रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इसलिए कमजोर तबकों के लिए बहुत करने के बावजूद गरीबी की गति और बढ़ी है।

माया : इस देश का भविष्य आपको कैसा दिखायी दे रहा है?

वेंकटरमण : (हंसकर) बहुत उज्ज्वल।

माया : क्या राष्ट्रपति भवन में आपसे मिलना सुलभ रहेगा?

वेंकटरमण : किसी भी आदमी के बारे में राय उसके पिछले व्यवहार के आधार पर बनती है।

माया : सामान्यतया राष्ट्रपति अपने को प्रेस से अलग रखता है, क्यों?

वेंकटरमण : हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं होता। मेरे पास ऐसा क्या है जो दे सकता हूं। जब सरकार में था, तो लोगों को बुलाता था और चाय के प्याले के साथ सब चीजों पर चर्चा करता था। लेकिन अब आपको मेरे से कोई मसाला नहीं मिल सकता।

माया : नये पद पर आपके सामने किस तरह की चुनौती आ सकती है?

वेंकटरमण : मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मेरे सामने कोई समस्या नहीं होगी। ■

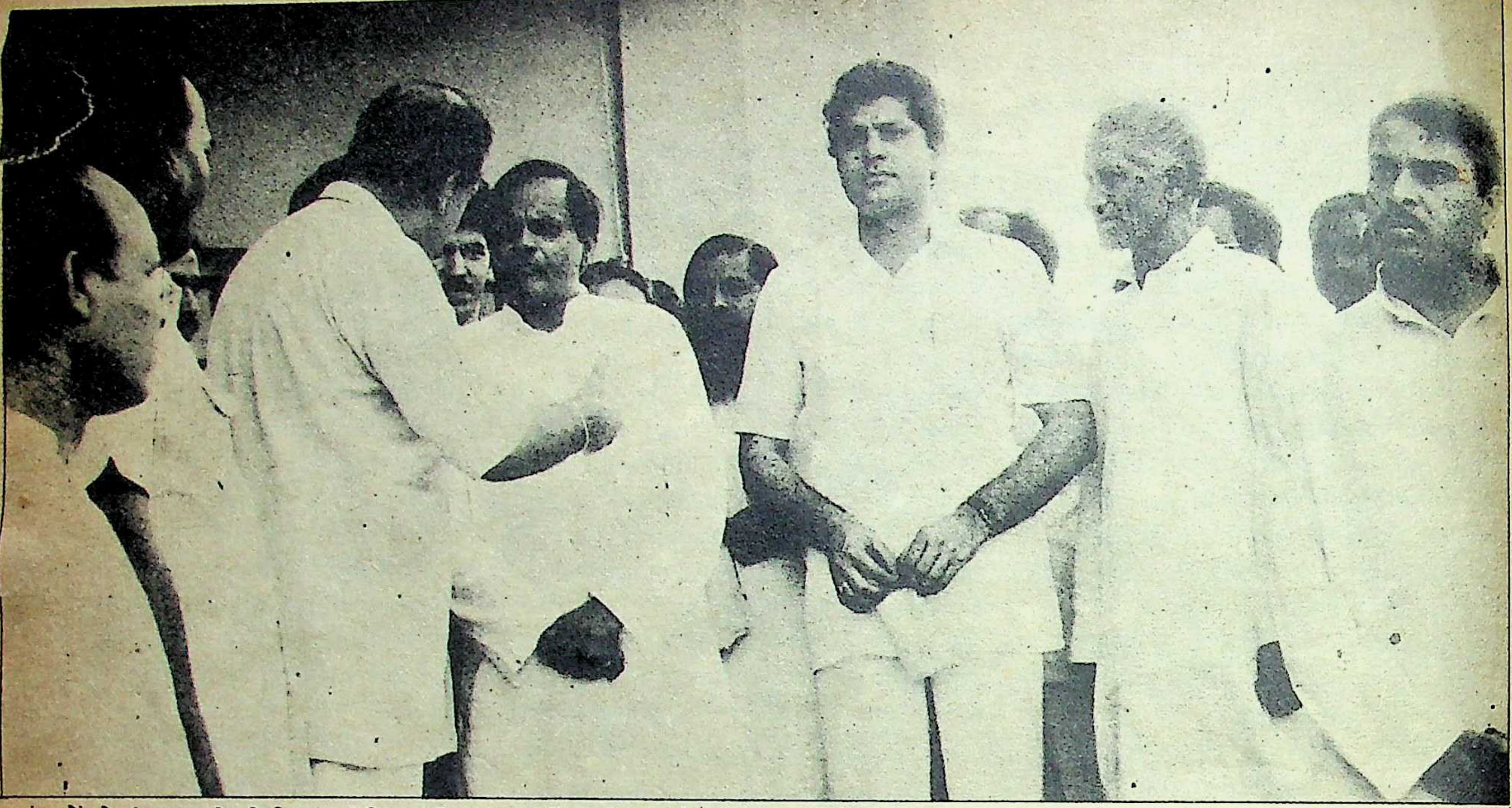

असंतुष्टों को संतुष्ट करने की विफल कोशिश : वीर बहादुर सिंह और उनके बायें जफर अली नकवी

वीर बहादुर सिंह के खिलाफ खुली बगावत

राजीव गांधी की 'हिटलिस्ट' में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का नाम सबसे ऊपर आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंका विधानमंडल दल के ३०३ सदस्यों (२६८ विधानसभा और ३५ विधान परिषद सदस्य) में से करीब १५० ने वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है। विद्रोहियों में ६ मंत्री भी हैं। यद्यपि तैयारी पहले से थी, लेकिन संयोग से अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद के निष्कासन और उसकी प्रतिक्रिया में राजा मांडा के 'इस्तीफे' के बाद यह 'बगावत' एक बड़ा राजनीतिक धमाका है। यद्यपि मुख्यमंत्री ने दो मंत्रियों—जफर अली नकवी और सुरेन्द्र सिंह—को हटा दिया है, लेकिन इससे क्या विद्रोह का दमन हो सकेगा ?

आखिर अब तक सब कुछ 'ठीकठाक' ढंग से चला रहे वीर बहादुर सिंह को अचानक ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा है। इस बारे में असंतुष्ट गुट के एक प्रमुख विधायक, सहारनपुर के मोहम्मद असलम खां कहते हैं, "वीर बहादुर ने पार्टी विधायकों का जितना अपमान किया है, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री, विरोधी दल के विधायकों को जितना सम्मान देते हैं, उससे कहीं ज्यादा उपेक्षा सत्ता पक्ष के सदस्यों की करते हैं। विधायकों का यही असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है।"

लेकिन इंका विधायकों की वीर बहादुर सिंह से नाराजगी का केवल यही एक कारण हो, ऐसी बात भी नहीं है। वास्तव में, हरियाणा में इंका की जबरदस्त पराजय के बाद उत्तर प्रदेश के इंकाई विधायकों का असंतोष व्यक्त करने का हौसला काफी बढ़ा है। पिछले दिनों विश्वनाथ प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह ने जो नाकेबंदी की थी और जिसके नतीजे में उनके प्रति जो सहानुभूति और सम्मान बढ़ा है, उसके कारण भी असंतुष्टों को अच्छा मौका मिल गया है।

अभियान का श्रीगणेश : वीर बहादुर सिंह हटाओ अभियान का विधिवत श्रीगणेश एक भोज में हुआ। राजा मांडा के सम्मान में १० जुलाई की रात्रि को लखनऊ में राज्यमंत्री जफर अली नकवी के सरकारी आवास पर ('विद्रोही' दावतों पर वीर बहादुर सिंह द्वारा लगायी गयी पाबंदी के बावजूद) भोज आयोजित किया गया था।

९ जुलाई को रात्रि में विश्वनाथ प्रताप सिंह दिल्ली से अचानक लखनऊ आ गये थे। सार्वजनिक रूप से अपने आने का कारण यह बताया था, "एक तो मैं डाक्टर को अपना दांत दिखाने आया हूं, दूसरा यहां पार्टी विधायकों में यह प्रचार करूंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वेंकटरमण को भारी बहुमत से जिताया जाये।"

इस बीच वीर बहादुर मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा राजा के प्रबल समर्थक जफर अली नकवी ने अपने सरकारी आवास पर एक भोज आयोजित कर डाला। इस बारे में नकवी का कहना था, "राजा, हमारी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनके सम्मान में भोज का आयोजन पार्टी-नीतियों के विरुद्ध नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी भोज के आयोजन पर प्रतिबंध का प्रश्न है, तो मुझे पार्टी अध्यक्ष या मुख्यमंत्री का ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।"

जब वीर बहादुर को इस भोज के आयोजन की जानकारी मिली, तो उन्होंने फौरन अपने कुछ मंत्रियों

शक्ति-परीक्षण : इंका अध्यक्ष महावीर प्रसाद से पंजा लड़ाते असंतुष्ट नेता मोहम्मद असलम खां

को निर्देश दिया, “आप लोग अपने यहां विधायकों को भोजन पर बुलाइये, ताकि कोई विधायक, नकवी के यहां न जा सके।” मंत्रियों के यहां रजिस्टर रखवा दिये गये, ताकि विधायकों के दस्तखत लिये जा सकें।

विधायकों की इस घेराबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में इंका विधायक नकवी के यहां भोज में शामिल हुए। सुनील शास्त्री ने भोज के बजाय इंका विधायकों को अपने कार्यालय में शाम की चाय पर बुलाया। उनसे रजिस्टर पर दस्तखत कराये और आनन-फानन चाय पार्टी समाप्त कर नकवी के यहां भोज में पहुंच गये। इसी तरह संजय सिंह ने एक होटल में विधायकों को भोज दिया था। उन्होंने यह भोज रात्रि साढ़े आठ बजे तक इसलिए समाप्त कर दिया, ताकि जो विधायक नकवी के यहां जाना चाहें, आसानी से जा सकें। नकवी के यहां भोज में पहुंचने वाले विधायकों ने यह माना कि वे या तो संबंधित मंत्री के यहां रखे रजिस्टर पर दस्तखत करके आये हैं या फिर लौटकर दस्तखत कर देंगे, क्योंकि मंत्री की नौकरी का सवाल है। यद्यपि संजय सिंह खुद तो जफर के यहां भोज में नहीं गये, लेकिन उन्होंने पार्टी विधायकों से खुलकर कहा, “यह शक्ति-परीक्षण का मौका है, आप सबको नकवी के यहां जरूर जाना चाहिए।”

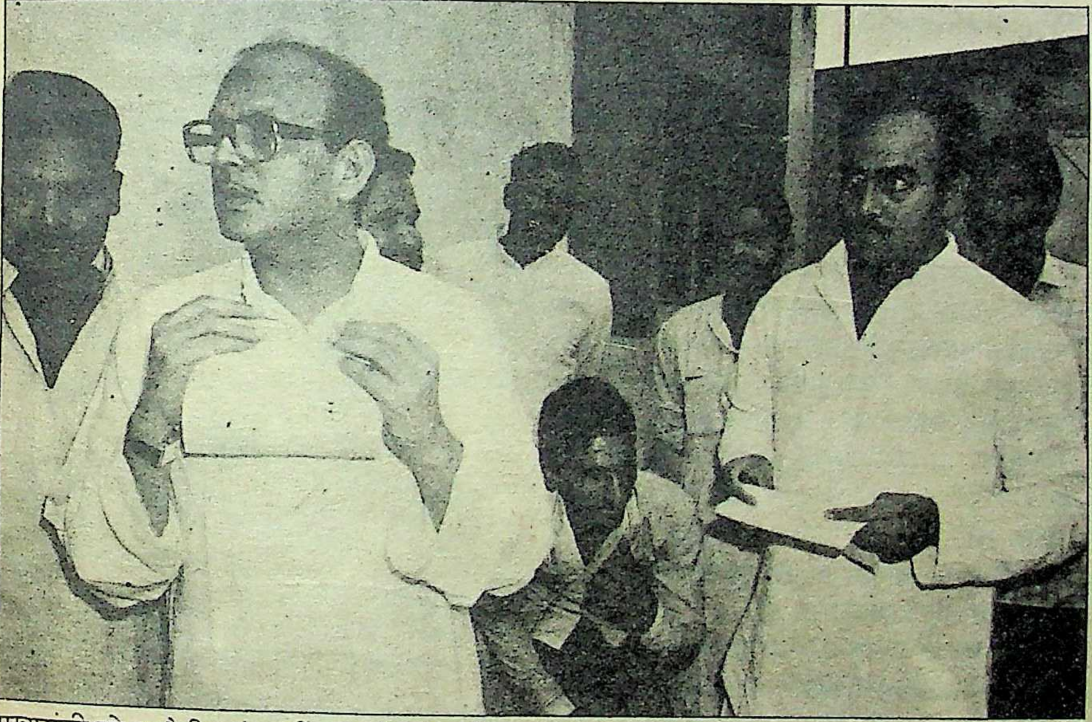

मुख्यमंत्री को चुनौती : संजय सिंह व वी०पी० सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

नकवी के यहां आयोजित भोज, यद्यपि रात्रि ८ बजे प्रारंभ होना था, लेकिन राजा मांडा स्वयं ही काफी विलंब से लगभग साढ़े नौ बजे पहुंचे। जो १०४ विधायक इस भोज में शामिल हुए थे, उनमें प्रमुख रूप से डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, सच्चिदानंद बाजपेई, जयदीप सिंह बरार, सैयद अली अशरफी, भोला सिंह, अधीर दुबे, तेज बहादुर गंगवार, सरयू प्रसाद सरोज, मोहम्मद असलम खां, दीपक कुमार, नागेंद्र नाथ सिंह, भगवती सिंह विशारद, श्यामलाल, सूर्यवीर सिंह, राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, नरेंद्र पाल सिंह, कुंवर देवेंद्र सिंह, कोकब हमीद, कैप्टन बल्देव सिंह, कर्नल केशरी सिंह, रमाकांत मिश्र, सरदार दलजीत सिंह, वीरेंद्र दीक्षित, राजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और विश्राम दास थे। इनके अतिरिक्त राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह और ऊर्जा मंत्री सुनील शास्त्री भी शामिल हुए। राज्यमंत्री ओम प्रकाश रिछारिया और हुकुम सिंह ने भोज में भाग तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने फोन पर नकवी को इस भोज के लिए अपना समर्थन जरूर दिया।

भोज में मौजूद विधायकों में अधिकांश बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने कहा, “अगर राजा मांडा को पार्टी से निकालने की कार्यवाही की गयी, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।” यद्यपि इस भोज में कोई खास राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, किंतु विधायकों को यह कहते जरूर सुना गया, “अगर वीर बहादुर सिंह इसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे, तो अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश की हालत हरियाणा से भी बदतर होगी।”

जफर अली नकवी इस भोज के बारे में कहते हैं, “उत्तर प्रदेश में कम-से-कम १५० पार्टी विधायक राजा के साथ हैं। बहुत से विधायकों को तो मैं इस भोज की सूचना नहीं दे सका था। कई विधायकों ने मुझसे शिकायत की कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया। तमाम विधायकों को तो कुछ मंत्रियों ने अपने यहां जबरन रोक लिया था।”

असतोष के कारण वीर बहादुर सिंह के विरोध के पीछे अलग-अलग मुद्दे हैं। असंतुष्टों में एक गुट तो उन लोगों का है जो कभी मंत्री रह चुके हैं और आज मंत्री-पद के सशक्त दावेदार हैं। पिछले डेढ़ वर्ष से वीर बहादुर सिंह उन्हें आश्वासन का ‘लाली पाप’ थमाये हुए हैं। डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, सच्चिदानंद बाजपेई, सुखदा मिश्रा, तेज बहादुर गंगवार, दीपक कुमार, गोपाल राम दास, दलजीत सिंह, रामरतन सिंह अपनी लगातार उपेक्षा के कारण असंतुष्ट हो गये हैं।

असंतुष्टों का दूसरा खेमा उन लोगों का है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के दावेदार लोग कर रहे हैं। संजय सिंह और सुनील शास्त्री खुले आम यह शिकायत करते हैं, “वीर बहादुर सिंह, हमारे बारे में तमाम-झूठी शिकायतें दिल्ली दरबार में करते हैं। वे हर मौके पर न केवल हमें काटने की कोशिश करते हैं, वरन् हमारे कामों में अड़ंगेबाजी भी लगाते हैं।

कुछ महीने पूर्व संजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि परिवहन निगम अब घाटे के बजाय मुनाफे में आ गया है। परिवहन सेवा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अगले ही दिन वीर बहादुर सिंह ने इस दावे को सार्वजनिक रूप से झूठा कह दिया था। वीर बहादुर सिंह शुरू से ही संजय सिंह को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते रहे हैं। यही वजह है कि संजय सिंह समर्थक विधायक खुलकर कहने लगे हैं, “वीर बहादुर सिंह के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में पार्टी की बची-खुची साख भी खतम हो जायेगी। इसलिए उन्हें हटाने के लिए हमने कमर कस ली है।”

असंतुष्टों का एक तीसरा गुट उन लोगों का है जो

वीर बहादुर सिंह मंत्रिपरिषद के सदस्य तो हैं, किंतु मुख्यमंत्री ने उन्हें 'अपंग' बना रखा है। ओम प्रकाश रिछारिया, सुरेंद्र सिंह, हुकुम सिंह, जफर अली नकवी ऐसे ही मंत्री हैं।

इस बारे में असंतुष्टों के नेता जफर अली नकवी कहते हैं, "राजीव गांधी एक शरीफ इंसान हैं। उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। किसी के नाम का हौवा (इशारा राजा मांडा की ओर) खड़ा करके अपनी कुरसी बचाने की कोशिश हो रही है।" नकवी को इस बात पर सख्त नाराजगी है कि मुख्यमंत्री ने अपने कई मंत्रियों के विरुद्ध इंटेलीजेंस ब्यूरो से फर्जी रिपोर्ट तैयार कराकर प्रधानमंत्री को भेजी है। इस तरह से वे तिकड़म की राजनीति कर रहे हैं जो ज्यादा दिन नहीं चल सकती है।

नकवी बताते हैं, "कहने को तो मैं वन राज्य मंत्री हूं, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। मेरा कोई भी आदेश अफसर मानता ही नहीं है। जो भी व्यक्ति मेरे पास किसी काम से आता है, तो मैं उससे कह देता हूं कि जैसा चाहे आदेश अपने हाथ से लिख लो, मैं दस्तखत कर देता हूं। आदेश का पालन हुआ या नहीं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री से करना।"

इंका के वरिष्ठ विधायक तथा भूतपूर्व मंत्री सच्चिदानंद बाजपेई अपने असंतोष को कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं, "आज प्रदेश में इंका की साख गिर रही है। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच रही हैं। इसी कारण विधायकों में छटपटाहट है। यह छटपटाहट केवल पार्टी विधायकों में ही है, ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री और विधायकों में यह छटपटाहट दिखाई पड़ती है। तिकड़म की राजनीति से न तो प्रशासन चलता है और न कुरसी बची रह सकती है। अगर यही हालत रही तो उत्तर प्रदेश भी हरियाणा बन जायेगा। दिल्ली की गणेश परिक्रमा को छोड़कर यदि मुख्यमंत्री जनहित के कार्यों में रुचि लें, तो स्थिति कुछ सुधर सकती है।"

इलाहाबाद के इंका विधायक सतीश जायसवाल तो खुले आम मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं। वे कहते हैं, "जन समस्याओं के समाधान में वीर बहादुर और उनकी सरकार पूरी तरह असफल रही है। भयंकर सूखा, विद्युत समस्या, पेयजल संकट के बारे में इलाहाबाद के सभी इंका विधायकों ने बार-बार वीर बहादुर का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे हमेशा मूकदर्शक बने रहे। वे (मुख्यमंत्री) समझते हैं कि पार्टी में अमिताभ बच्चन ही सब कुछ हैं। अब हम मुख्यमंत्री का यह रवैया नहीं चलने देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि वीर बहादुर को हटाकर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाये जो जनता की आकांक्षाओं के साथ-साथ राजीव गांधी के सपनों को सही ढंग से साकार कर सकें।"

वीर बहादुर सिंह हटाओ अभियान के एक प्रमुख स्तंभ तथा १९७४ से लगातार जीतते आ रहे इंका विधायक डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल को इस बात का अफसोस है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम से पार्टी नेतृत्व ने अभी तक कोई सीख नहीं ली है। अगर समय रहते संगठन को चुस्त और प्रशासन को दुरुस्त नहीं किया गया, तो हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश भी इंका के लिए 'वाटर लू' हो जायेगा। वे कहते हैं, "वीर बहादुर सिंह की प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। प्रदेश में नौकरशाही हावी हो गयी है। खुद मुख्यमंत्री ही जब पार्टी विधायकों की उपेक्षा करेंगे, तो अफसर मनमानी करने से क्यों चूकेगा?"

तिकड़म की राजनीति के खिलाफ : सच्चिदानंद

डाक्टर कौशल, पार्टी विधायकों में बढ़ रहे असंतोष के बारे में कहते हैं, "आज विधायकों को पार्टी की बैठक में अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष का विधायक विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले उठा नहीं सकता, किसी मंत्री की शिकायत नहीं कर सकता। इंदिराजी के समय में अगर मुख्यमंत्री कोई बात नहीं सुनता था, तो विधायक 'ऊपर' जाकर शिकायत करके अपनी 'भड़ास' निकाल लेता था। अब वैसा माहौल नहीं है। पार्टी विधायक जनहित के कार्य के लिए भी जब मुख्यमंत्री के पास जाता है, तो वहां से अपमानित होकर लौटता है।

इस सवाल पर कि वीर बहादुर सिंह को हटा कर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाये? डाक्टर कौशल कहते हैं, "अब वे दिन लद गये, जब विधानमंडल दल के सदस्य अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री चुनते थे। अब जो भी 'ऊपर' से थोपा जायेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाये जो जनहित के कार्यों में रुचि ले तथा सही ढंग से राजीव गांधी के सपनों को साकार करे।"

विधानसभा में हर आड़े मौके पर सरकार का बचाव करने वाले युवा विधायक जयदीप सिंह बरार, वीर बहादुर की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। वे बताते हैं, "दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को वीर बहादुर सिंह से फर्जी आंकड़े तैयार करने की कला सीख लेनी चाहिए। इसी कला के जरिये वे भी अपने प्रदेश को बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज हालत यह हो गयी है कि विकास कार्यों का ८० प्रतिशत धन अफसरों की जेब में जा रहा है।"

सहारनपुर के इंका विधायक तथा प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद असलम खां वीरबहादुर सिंह के कटु आलोचक हैं। इसी ११ जुलाई को लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान के सभागार में आयोजित इंका विधायकों की बैठक के बाद जब वीर बहादुर ने मोहम्मद असलम को 'पटाते' हुए कहा, "यह सब क्या कर रहे हो?" तो वह झट बोले, "पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। आपके रहते पार्टी कमजोर हो रही है।"

असलम खां बताते हैं, "वीर बहादुर को विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस इस बात में रुचि रहती है कि कैसे उनकी कुरसी बची रहे। यही वजह है कि अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच कोई तालमेल नहीं रह गया है। जिलों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का आयोजन जब अफसर करने लगे हैं, तो विधायकों और आम कार्यकर्ताओं को कौन पूछेगा। सही मायने में वीर बहादुर सिंह, इंका के मुख्यमंत्री न होकर विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हैं।"

असलम खां को इस बात का दुख है कि मेरठ का दंगा, जो प्रशासन की अक्षमता, अदूरदर्शिता और लापरवाही के कारण हुआ, वीर बहादुर सिंह उसे विदेशी षड्यंत्र कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। "अच्छा होता कि नैतिकता के आधार पर वीर बहादुर सिंह इस्तीफा देकर इंका की छवि को बिगड़ने से बचा लेते।"

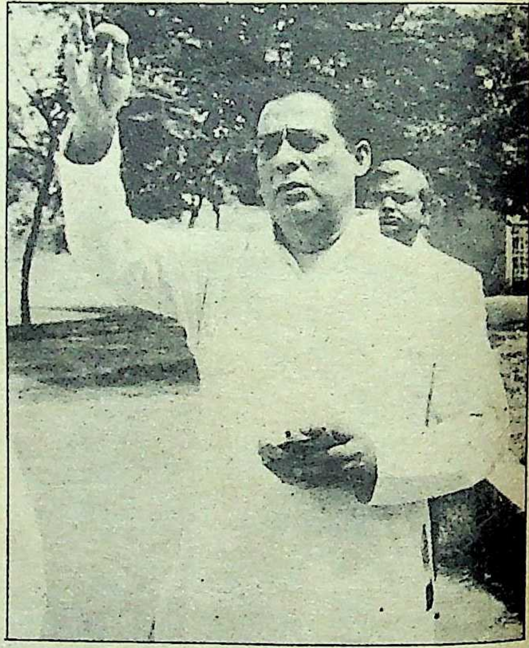
हरियाणा से सबक लेना चाहिए : डा० कृष्णवीर

इस तरह की शिकायत करने वाले अकेले मोहम्मद असलम खां ही नहीं हैं। इंका के अधिकांश विधायकों, जिनमें सैयद अली अशर्फी, तेज बहादुर गंगवार, भोला सिंह, हाजी वसीम अंसारी, अधीर दुबे, वीरेंद्र दीक्षित, रामरतन सिंह प्रमुख हैं, ने 'माया' से कहा, "उत्तर प्रदेश को हरियाणा होने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि जल्द-से-जल्द प्रदेश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाये जो तिकड़म की राजनीति के बजाय जनसमस्याओं के समाधान में रुचि ले।"

सैयद अली अशर्फी बताते हैं, "मुख्यमंत्री सचिवालय में लोकदल के विधायक शतरुद्रप्रकाश के सिफारिशी पत्र निकलवा कर देख लीजिए। मुख्यमंत्री

ने उनके हर पत्र पर अपनी कलम से आदेश किये हैं, जबकि पार्टी विधायकों से मुख्यमंत्री सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं।"

एक मात्र कार्य : आज उत्तर प्रदेश में स्थिति यह हो गयी है कि मुख्यमंत्री-समर्थक खेमा असंतुष्टों को पटाने में लगा है, जबकि असंतुष्ट अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। यही वजह है कि वीर बहादुर सिंह कल तक जिन विधायकों से मिलना गवारा नहीं करते थे, आज वह उनके सामने हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। ११ जुलाई को उन्होंने डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन डाक्टर कौशल थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पुट्ठे पर हाथ तक रखने नहीं दिया।

"अगले विस्तार में मैं तुम्हें मंत्री जरूर बनाऊंगा," इस तरह के आश्वासन लगभग हर पार्टी विधायक को वीर बहादुर दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में मोहम्मद असलम खां और जयदीप सिंह बरार कहते हैं, "हर किसी को मंत्री बना देना समस्या का समाधान नहीं है। वीर बहादुर को अपने सोचने-समझने का तरीका बदलना चाहिए। विधायकों में असंतोष इसलिए नहीं है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। असंतोष तो इसलिए है कि जनहित के काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, विधायक अपने क्षेत्र में क्या मुंह लेकर जायें?"

हम जनता को क्या मुंह दिखायें : गंगवार

विधायक भोला सिंह, तेजबहादुर गंगवार और सुखदा मिश्र को सबसे ज्यादा शिकायत तो इस बात की है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कौन अफसर उनके गुट का है, कौन व्यक्ति उनके नजदीक है, कौन किस जाति का है—इस आधार पर न तो राजनीति चलती है और न प्रशासन। चित्रकूट में प्यास से दर्जनों लोग मर गये, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं। पंजाब में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के ४० तीर्थ यात्रियों को मार डाला, लेकिन वीर बहादुर ने यह भी पहल नहीं की कि मृतकों के प्रति विधानसभा में शोक संवेदना व्यक्त की जाये। विपक्षी दलों ने जब इस मसले पर सरकार की फजीहत करा दी, तो मुख्यमंत्री को होश आया।

इंका के हरिजन विधायक भी वीर बहादुर से खुश नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के इंका विधायक तथा भू०पू० राज्यमंत्री दीपक कुमार कहते हैं, "हरिजनों की जितनी उपेक्षा इस सरकार ने की है, उतनी इसके पहले कभी नहीं हुई। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। इस प्रभाव को कैसे समाप्त किया जाये, इस पर विचार के लिए कुछ महीने पहले वीर बहादुर सिंह ने हरिजन विधायकों की एक बैठक कुकरैल पिकनिक स्पाट पर बुलायी थी। विधायकों ने इस बैठक में जो सुझाव दिये थे, उन पर अमल करना तो दूर उन सुझावों के 'नोट्स' तक नहीं तैयार किये गये। हकीकत तो यह है कि वीर बहादुर सिंह को हरिजन विधायकों पर विश्वास नहीं है। वे हर हरिजन विधायक को डी०एस० फोर का आदमी मानते हैं। भला, अविश्वास की भावना से कहीं काम होता है।"

अकेले राजा नहीं उत्तर प्रदेश के असंतुष्टों को हवा देने का काम केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वीर बहादुर सिंह के विरोधियों में नारायण दत्त तिवारी, मोहसिना किदवई और जियाउर्रहमान समर्थक इंका विधायक भी शामिल हो गये हैं। सुखदा मिश्रा, रघुवीर सिंह यादव, तेज बहादुर गंगवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारायण दत्त तिवारी-समर्थक माने जाते हैं। जो मुस्लिम विधायक वीर बहादुर सिंह के खिलाफ हैं, उनमें अधिकांश मोहसिना किदवई और जियाउर्रहमान के नजदीक समझे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों में केवल शीला दीक्षित और राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का ही समर्थन फिलहाल वीर बहादुर सिंह को मिल रहा है।

वैसे, वीर बहादुर सिंह समर्थक विधायक, असंतुष्टों के मुख्यमंत्री हटाओ अभियान को 'पानी का बुलबुला' मानते हैं। वीर बहादुर के प्रबल समर्थक देवरिया के इंका विधायक राम सकल तिवारी कहते हैं, "तथाकथित असंतुष्ट, दबाव और 'ब्लैक मेलिंग' की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। अभी भी इंका विधान मंडल दल के ७५ प्रतिशत से अधिक विधायक, हमारे नेता वीर बहादुर सिंह के साथ हैं। तथाकथित असंतुष्ट चाहे दिल्ली में या कहीं भी परेड करें, हमारा नेता मजबूत और सक्षम है। उसे हटाने या नेतृत्व परिवर्तन का कहीं कोई सवाल नहीं है।"

राम सकल तिवारी की धारणा निराधार नहीं कही जा सकती। असंतुष्ट विधायक भी यह जानते हैं कि किसी के विरोध से न तो कोई मुख्यमंत्री बदला जाता है और न विधायकों का बहुमत प्राप्त व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। इंका शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने और बदलने का काम केवल दिल्ली की 'इच्छा' पर निर्भर है। अगर असंतुष्टों के मुख्यमंत्री हटाओ अभियान के कारण मुख्यमंत्री बदल सकते, तो उड़ीसा और बिहार के मुख्यमंत्री कब के बदल चुके होते। बिहार में तो असंतुष्टों को हवा देने का काम जगन्नाथ मिश्र जैसे शक्तिशाली नेता कर रहे हैं। उड़ीसा में जानकी बल्लभ पटनायक को हटाने की मांग को लेकर वहां के असंतुष्ट इंकाई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा चुके हैं। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा।

विकल्प : "उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर के स्थान पर आप किसे मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं?" इस सवाल के जवाब में हर असंतुष्ट विधायक ने यही कहा, "हाईकमान जिसे बनायेगा, उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि नेता ऊपर से न थोपकर विधानमंडल दल से ही बनाया जाये।"

असंतुष्टों में कई विधायक इस पक्ष के हैं कि नारायण दत्त तिवारी को फिर से प्रदेश की बागडोर सौंपी जाये। इस राय के साथ वे यह भी तर्क देते हैं कि अगर लोकसभा के किसी सदस्य जैसे ब्रह्मदत्त, राजमंगल पाण्डेय, मोहसिना किदवई, बलराम सिंह यादव या के०सी० पंत को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश भेजा गया, तो उनके द्वारा रिक्त होने वाली लोकसभा सीट पर दुबारा इंका का जीतना मुश्किल पड़ेगा। सांसद से मुख्यमंत्री बने व्यक्ति को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा और प्रदेश में विधानसभा की केवल एक सीट टांडा (फैजाबाद) में रिक्त है। वहां से अगर सांसद मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, तो काफी बदनामी होगी। जहां तक नारायण दत्त तिवारी का प्रश्न है, वे राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी उत्तर प्रदेश-वापसी पर जहां लोकसभा की किसी सीट पर चुनाव नहीं होगा वहीं तिवारीजी टांडा से चुनाव भी जीत जायेंगे। लेकिन इसके विपरीत अधिकांश असंतुष्ट विधायक, विधानमंडल दल से ही नेता चुने जाने के पक्ष में हैं। ऐसे विधायकों का कहना है, "विश्वनाथ प्रताप सिंह को काटने के लिए यह अच्छा रहेगा कि संजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाये।"

बहरहाल, बड़ी-से-बड़ी समस्या के बावजूद निश्चित और मस्त होकर कुरसी पर पलथी मार कर बैठे रहने वाले वीर बहादुर सिंह असंतुष्टों की बढ़ती गतिविधियों से कतई परेशान नहीं हैं। जोड़-तोड़ और तिकड़म की राजनीति में माहिर वीर बहादुर इस बारे में कहते हैं, "कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ अखबार में है। हमारे यहां कोई असंतुष्ट नहीं है। अखबार वाले तो बढ़ा-चढ़ा कर लिखते रहते हैं। मैं इन सब खबरों पर कोई ध्यान नहीं देता हूं। मैंने कह दिया है जो कोई अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उसे निकाल बाहर करूंगा। राष्ट्रपति के चुनाव में सबने देख लिया है। जितने हमारी पार्टी के विधायक हैं, उससे ज्यादा वोट वेंकटरमण को मिले हैं। अखबारवाले झूठें हवा उड़ावत हैं। जो एक-दो लोग कुछ बोलने लगे हैं। वे ठीक हो जायेंगे। मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद सब ठीक हो जायेगा।"

कुलांटी मारने में माहिर वीर बहादुर सिंह असंतुष्टों के इस मसले पर क्या गुल खिलायेंगे, यह उनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आरिफ मोहम्मद खां और अरुण नेहरू के निष्कासन के विरोध में वी०पी० सिंह के इस्तीफे के बाद स्थितियों ने महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। हाईकमान पसोपेश में है, क्योंकि उपर्युक्त तीनों सांसद उत्तर प्रदेश के हैं और वी०पी० सिंह से पहली घमासान लड़ाई इसी प्रदेश में लड़नी है। इसलिए यदि वीर बहादुर सिंह को हटाते हैं, तो असंतोष का एक केंद्र और पैदा हो जायेगा और यदि नहीं हटाते हैं, तो असंतुष्टों को सीधे वी०पी० के पाले में धकेलना होगा। लेकिन यह पसोपेश की स्थिति महंगी पड़ सकती है, इसलिए वीर बहादुर सिंह के भविष्य का फैसला अविलंब करना होगा।

—अजय कुमार

छाया : राजेंद्र कुमार

आज का मिथिलांचल

राजा जनक और भगवती सीता के कारण पूरे देश की आस्था से जुड़ा मिथिलांचल किसी जमाने में अपनी समृद्धि, भव्य नगरों, उद्‌भट विद्वानों, श्रेष्ठ शिक्षा केन्द्रों और साहित्य-संगीत-कला में रचे-बसे अलमस्त मैथिलवासियों के कारण विश्वविख्यात था, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत क्यों हो गयी है कि यह देश ही इस क्षेत्र को भूलता जा रहा है, अभावों से ग्रस्त यहां के निवासी 'भुखले रहब त सुतले रहब' कहते हुए निराश हो चुके हैं और राजनेता सुख-स्वप्न दिखाते हुए इनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रस्तुत है मिथिलांचल के अतीत और वर्तमान का लेखा-जोखा **विकास कुमार झा** द्वारा :

राजा जनक की राजधानी के रूप में चर्चित मिथिला का क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी और पश्चिम में गंडक तक फैला हुआ था। बृहद् विष्णु पुराण के मुताबिक कोसी नदी से गंडक नदी तक मिथिला क्षेत्र की पूर्वी-पश्चिमी लंबाई ९६ कोस और गंगा से लेकर हिमालय तक चौंसठ कोस चौड़ी थी। मध्य युग में मिथिला को 'तीरभुक्ति' तथा आजकल इसे 'तिरहुत' कहा जाने लगा है। इसके अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगुसराय और नेपाल के सप्तरी, महोत्तरी, मोरंग और सरलाही आदि जिले आते हैं, लेकिन मिथिला का सर्वाधिक चर्चित केंद्र 'दरभंगा' है, जो कमिश्नरी और मुख्यालय भी है। इतिहासकार पी०सी० राय चौधरी का मानना है कि 'दरभंगा' का नामकरण 'द्वारबंग' या 'दर-ए-बंगाल' से हुआ।

स्मरणीय अतीत: मिथिला, अपनी साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत के लिए भी कम मशहूर नहीं है। उसने महामहोपाध्याय सर डा० गंगानाथ झा और उनके सुपुत्र डा० अमरनाथ झा जैसे शिक्षाशास्त्रियों और विद्वानों को जन्म दिया। ये दोनों महापुरुष प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आरूढ़ तो रहे ही, साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी, मिथिला और मैथिली भाषा का भी मान बढ़ाया।

सामाजिक संबंधों को लेकर भी मिथिला की परंपराएं अत्यंत स्वस्थ रही हैं। चाहे ब्राह्मण हों या राजपूत या कायस्थ या निम्न जातियों के लोग, सभी में बड़ा सौहार्द रहा है। मुसलमानों की संख्या भी वहां कम नहीं है। सांप्रदायिक सद्‌भाव का तो यह आलम है कि बहुत से मैथिल ब्राह्मण अपने आप को 'खां' लिखते हैं। मुसलमानों के त्योहारों, खासकर मुहर्रम में वहां के हिंदू बराबर शरीक होते हैं। यही नहीं, मुसलमान तो 'मरसिया' भी मैथिली में ही गाते हैं—

'एहि दसो दिन सैयद
बंसवा कटेल कै रे हाय।
से हो बंसवा भेलै बिसरनमारे हाय।'

मिथिला की संस्कृति वहां की वेशभूषा ही नहीं, आभूषणों तक में झांकती थी। मैथिल ब्राह्मणों और कायस्थों में मिरजई, चपकन विशेष लोकप्रिय रही। कंधों पर डेढ़ पटी दोपट्टा, चादर और सिर पर पगड़ी धारण करना तो उनकी सांस्कृतिक शान रही है। राजपूतों में ताखी और शेरवानी का जोर रहा। ऐसे ही स्त्रियों में पुराने पहिनावों की भी ललक रही। अपने बच्चों को वे पहले 'धरिया' या 'बिष्ठी' पहनाना अच्छा समझती थीं। औरतें अपने सिंगार के गहनों में बिजौट, पाति, जौसन, बाजू, झुम्मक, कर्णफूल, कंठा, छक, बुलकी और नकमुन्नी आदि पहनती थीं। बच्चों को मांएं कारा माठा और लबंग पहनाना उनके प्रति दुलार मानती थीं।

दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
बेला, दरभंगा
DARBHANGA INDUSTRIAL AREA DEVELOPME
जवानी

उद्योग शून्य हैं

मिथिलावासियों की आत्मा धर्म में ही सच्चा सुख पाती रही है। शिव और पार्वती उनके प्रमुख आराध्य रहे हैं। गृहिणियां सुबह-सुबह ही मिट्टी का महादेव बनाकर पूजती थीं। शक्ति के प्रति हर गृहिणी अपना अनुराग 'जय-जय भैरवि असुर भयाउनि, पशुपति भामिनि माया' गाकर जताती रही हैं। बच्चों की पढ़ाई का श्रीगणेश भी 'शक्ति देवी' के श्लोक से ही करवाया जाता रहा। पूरे मिथिला में विशेष उत्सवों पर 'अरिपन' (पृथ्वी पर बनाये गये तांत्रिक चक्रादि) बनाने की परंपरा रही है। इनमें तुसारी पूजा का अरिपन, पृथ्वी अरिपन, सांझ अरिपन, दशपात अरिपन, मधु श्रावणी अरिपन, अष्टदल अरिपन मिथिला की गृहिणियों की लोक रुचि के अनुसार रहे हैं। शुभ मुहूर्तों पर 'दुर्वाच्छत' की परंपरा भी रही है। मिथिलावासियों के शादी-विवाह, तीज-त्योहार, मुंडन-जनेऊ, श्राद्ध आदि सभी यम-नियम से होते रहे हैं।

गप्प लड़ाने और मधुर भोजन के भी मिथिलावासी शौकीन रहे हैं। माछ, मखान, दही-पान आदि उन्हें विशेष प्रिय हैं। चूड़ा-दही तो उनका प्रतिदिन का व्यंजन है। अतिथियों को तो वे भगवान मानते हैं। अतिथियों के लिए 'सचार' (दर्जनों व्यंजन) लगाये जाने की प्रथा रही है। जिनके साथ उनके रक्त संबंध होते हैं, उन्हें वे 'सौजन भोजन' यानी चावल-दाल आदि (सिद्ध भोजन) तथा

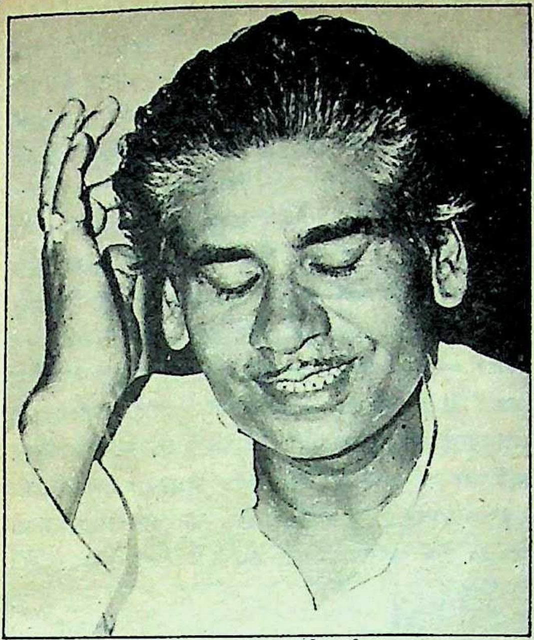

राजा सलहेस और दीना भद्री की उपेक्षा:
विधायक महावीर प्रसाद

जिनके साथ रक्त संबंध नहीं होते, उन्हें 'असौजनिया' यानी चूड़ा-दही (असिद्ध भोजन) खिलाने का प्रचलन रहा है। शादी-विवाह के मामलें में भी वे सादगी बरतते रहे हैं। कीर्तनियां नाटक और जटा-जटिन के गीत मिथिलावासियों के मनोरंजन के साधनों में रहे हैं। शादी-विवाह के अवसर पर 'कोहबर' (जिसमें नवदंपति रहते हैं) में 'पुरइन' बनाने का रिवाज भी रहा है। ऐसे अवसरों पर दीवारों पर मिथिला चित्रकला भी अंकित की जाती रही। नवदंपतियों के 'कोजागरा' पर्व में दामाद के घर पीढ़ी पर मनोरम चित्रों को बनाकर, मधुर पकवानों सहित भेजे जाने की परंपरा रही है।

दुखदायी वर्तमान : ऐसी सुंदर सामाजिकता और मधुर सांस्कृतिक गरिमा की गौरव 'मिथिला' आज क्यों अपनी अस्तित्व-रक्षा के लिए परेशान है? इसके कारण एक नहीं, अनेक हैं। कहते हैं, मिथिला ने जिन राजनेताओं को उसने अपना समझकर जिताया, उन्होंने ही उसकी पीठ में छुरा भोंका। अपनी राजनीतिक गुट्टियों के आगे 'मिथिला' की किसे पड़ी है? मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और दरभंगा के पूर्व सांसद सुरेंद्र झा 'सुमन' कहते हैं, "मैथिलों की नयी पीढ़ी अपनी अस्मिता का आनंद नहीं उठा रही। मिथिला में आज-न-कल अपनी सुदीर्घ उपेक्षा व अपमान के खिलाफ आंदोलन जरूर उठेगा। हमारा मंशा पृथक्तावादी नहीं पर, आज एक अलग मिथिला प्रांत की आवश्यकता है। अगर हरियाणा जैसा छोटा प्रांत इतना विकास कर सकता है, तो मिथिला को भी यह अवसर मिलना चाहिए। मैथिलों की आबादी तीन करोड़ से अधिक है। इतनी आबादी का एक अलग प्रांत क्यों नहीं हो सकता? बिहार जब बंगाल से अलग हो रहा था, उस समय मिथिला के चिंतक स्व० मुरलीधर झा ने कहा था कि इस प्रदेश का नाम बिहार न होकर 'मगधमिथिला' होना चाहिए। आजादी के बाद १९५५ के जमाने में बाबू जानकी नंदन सिंह सरीखे मिथिला के नेताओं ने अलग मिथिला प्रांत की मांग की थी। जब सरकार ने 'भाषावार प्रांत आयोग' का गठन किया था, उसमें भी 'मैथिल महासभा' की ओर से आयोग को इस आशय का ज्ञापन दिया गया था।

सुमनजी आगे कहते हैं, "सही मायने में मिथिला के लोग स्वभाव से विद्रोही होते ही नहीं। आजादी के बाद भी मिथिला को कोई लड़ाकू नेता नहीं मिला। नतीजतन, मिथिला विकास के लिए मोहताज रह गयी। हां, स्व० ललित नारायण मिश्र ने मिथिला के विकास में काफी रुचि ली और थोड़े समय में उन्होंने उपेक्षित मिथिला के लिए काफी कुछ करने की कोशिश भी की। उनके निधन के बाद जब उनके अनुज डा० जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो मिथिला को उनसे जितनी अपेक्षा थी, वे उसे पूरी न कर सके। स्व० ललित नारायण मिश्र के सुपुत्र विजय कुमार मिश्र को दरभंगा के लोगों ने उसी भावना से संसद में जिताया, पर उन्होंने और अधिक निराश किया। भाषाई स्तर पर भी 'मैथिली' की स्थिति अति दयनीय है। लगभग तीन दशक से मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम् अनुसूची में शामिल करने की गुहार हो रही है, पर कुछ भी नहीं हो सका। मैथिली के अष्टम् अनुसूची में आने से भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में मैथिली भी शामिल हो जायेगी और मिथिला के युवक बड़ी संख्या में प्रशासनिक सेवा में आ सकेंगे।

मध्य व उच्च वर्ग ने जहर घोला:
मैथिली के साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर

मिथिला के पास अभी तक कायदे का अपना एक दैनिक या साप्ताहिक नहीं हो सका। कई साल पूर्व डा० जगन्नाथ मिश्र ने मैथिली-भाषियों की संस्था 'चेतना समिति' के मंच से एलान किया था कि वह मैथिली का एक दैनिक निकालेंगे। उन्होंने अपना हिंदी दैनिक तो शुरू कर दिया पर मैथिली दैनिक की बात साफ भूल गये। 'इंडियन नेशन-आर्यावर्त पत्र-समूह' के मालिक दरभंगा के राजकुमार शुभेश्वर सिंह ने अपने साप्ताहिक 'मिथिला-मिहिर' को दैनिक तो कर दिया, पर वह उसे चला नहीं सके। दरभंगा से मैथिली दैनिक 'स्वदेश' निकलता था, पर अर्थाभाव के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। मैथिली अकादमी की भी स्थिति दुखद ही है। समझिए, वह बेहोश पड़ी है। नाकाबिल लोग वहां बैठकर मैथिली के हक से खेल रहे हैं।

लुप्त होती संस्कृति : इधर के सांस्कृतिक माहौल में ही अंतर आने लगा है। मिरजई, चपकन और पाग का युग गया। शादी-विवाह के मौके पर दूल्हा अपने बुजुर्ग अभिभावकों की जिद पर खिसियाकर केवल रस्म अदायगी के लिए पाग भले ही बांध ले, स्वेच्छा से नहीं। ऐसे ही, ठेठ मिथिला की संस्कृति आज भी जिन गांवों में बची है, वहां की बूढ़ी औरतें ब्लाउज पहनना पाप-सरीखा मानती थीं, लेकिन नये जमाने की बहुओं ने उन्हें समझा-बुझाकर अब राजी कर लिया है। पहले मिथिलावासी बच्चों को 'धरिया' या 'बिष्ठी' पहनाना आवश्यक समझते थे, लेकिन अब तो छोटी-से-छोटी औकात्वाला भी अपने बच्चों को 'धरिया' या 'बिष्ठी' पहनाने में तौहीन महसूस करते हैं। मिथिला की औरतें परंपरा से चले आ रहे आभूषणों को पहनने में सुख का अनुभव करती थीं, लेकिन आज वे आभूषण लुप्त होते जा रहे हैं। आज की मैथिल गृहिणियां तो अब धार्मिक कार्यों में भी दिलचस्पी नहीं लेतीं। कष्ट में पड़ने पर चाहे भले महाकवि विद्यापति या कविवर चंदा झा की 'नचारी' या 'महेशवाणी' उनके कंठ से फूट पड़े, लेकिन अब वह बात नहीं रही। पहले बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत और उनका अक्षर-ज्ञान, 'शक्तिदेवी' के श्लोक से कराया जाता था, लेकिन अब मैथिल पिता ही श्लोक भूल चुका है, तो बच्चे को क्या सिखायेगा। लिहाजा, आज का मैथिल शिशु 'साते भवतु' की जगह 'कैट-रैट' से विद्यारंभ करता है।

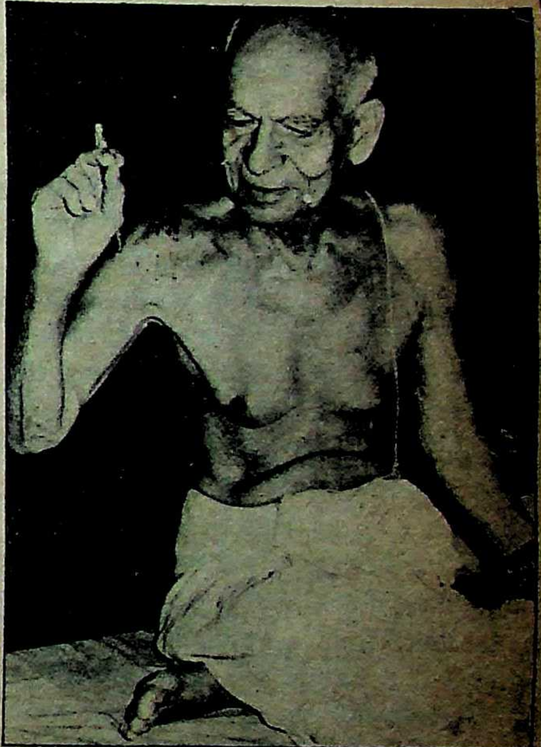

विस्मृत अस्मिता : सुरेन्द्र झा सुमन

पहले मिथिलावासियों में 'सौजन' [illegible] 'असौजनिया' भोजन का रिवाज था और वे [illegible] उसका पालन भी करते थे, लेकिन अब इसका [illegible] चक्कर नहीं रहा। पहले मैथिलों की शादी [illegible] से संपन्न होती थी, पर अब शादियां [illegible] संपन्न ही नहीं होतीं। पहले '[illegible] बिना श्रोत्रिय-ब्राह्मण [illegible]

लुप्त होती परम्परा:
'महफा' में शादी करने जा रहे नन्हें दूल्हे राजा!

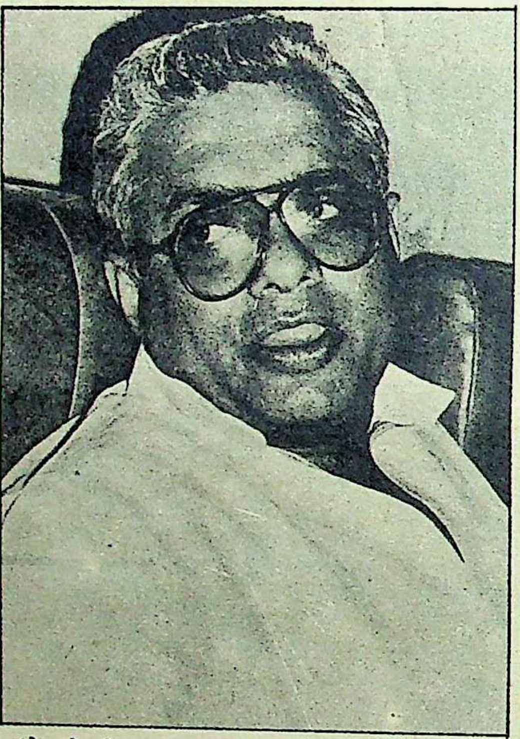

कांग्रेस ने धोखा दिया: सांसद विजय कुमार मिश्र

ये सब बातें केवल अतीत की स्मृतियां भर रह गयी हैं। इसी तरह शादी-विवाह की कितनी ही पारंपरिक बातें छूटती जा रही हैं।

पहले मैथिल गृहिणियां जहां 'अरिपन' की विशेषज्ञ होती थीं तथा मिथिला के विविध-व्यवहारों की 'डिक्शनरी' होती थीं, वहां अब की आधुनिकाएं अपनी पूर्वपरपंराओं से अनभिज्ञ हैं। यहां तक की उनमें कुछ जानने की अभिरुचि ही नहीं रह गयी है। इसी तरह, अब तो नयी पीढ़ी में 'दुर्वाच्छत' मंत्र जाननेवाला कोई नहीं मिलता। जनेऊ बनाना, उसे मंत्रसिक्त करना और धारण करना तो दूर की कौड़ी ही है।

कहना पड़ेगा कि इधर मिथिला की संस्कृति निरंतर छीजती चली जा रही है, लेकिन नये दौर का मैथिल युवा अपनी संस्कृति के इस क्षय से बेखबर है। मैथिली के चर्चित साहित्यकार और अकादमी पुरस्कार विजेता चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' कहते हैं, "मैथिलों का मध्य व उच्च मध्यवर्ग अपनी संस्कृति को उपहास का विषय मानता है और इसी तबके ने सबसे ज्यादा जहर घोला है। मिथिला में जब तक प्राथमिक शिक्षा मैथिली भाषा के माध्यम से नहीं होगी, तब तक मिथिला का भविष्य नहीं संवरेगा। मैथिलों को अपने साहित्य के प्रति भी सचेत व जागरूक होने की आज सख्त जरूरत है। दरभंगा में आकाशवाणी है, पर वहां मैथिली की घोर उपेक्षा है। जैसे कृषि-कार्यक्रम में बहुत सारी बातें ऐसी शब्दावली में कही जाती हैं, जिसे मिथिला का किसान समझ ही नहीं पाता। एक उदाहरण देखिए— 'बिचड़े सूख रहे हैं। ठेठ मैथिल किसान जल्दी समझेगा ही नहीं कि यह 'बिचड़े' क्या होता है? इसलिए ऐसे कार्यक्रम मैथिली में ही होने चाहिए।

मिथिलावासी आलसी भी खूब होते हैं। सी०एम० कालेज, दरभंगा के मैथिली व्याख्याता डा० भीमनाथ तो कहते हैं कि मैथिलों में 'भुखले रहब त सुतले रहब' वाली कहावत खूब प्रचलित है। इसके अलावा कोढ़ में खाज यह कि मिथिला को जितने मिले सभी राजनीतिक सौदागर ही मिले। नतीजतन, उन लोगों ने भावुक मैथिलों का अच्छा-खासा शोषण किया। पुल बनवाने, सड़कें बनवाने तथा पेयजल की समस्या पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मिथिला में शिक्षा की तो और दुर्दशा है। पहले मिथिला में गांव-गांव में संस्कृत की शिक्षा 'टोले' विद्यालयों में दी जाती थी, लेकिन आजकल स्थिति बिलकुल भिन्न है। सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए कागज पर हजारों संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं। दरभंगा जिले के क्योटी क्षेत्र के विधायक कलीम अहमद कहते हैं, "शिक्षा को लेकर देशभर में प्रसिद्ध मिथिला में अब शिक्षा ही शून्य हो गयी है। जो हालत मिथिला के रैयाम व लोहट चीनी मिल तथा अशोक पेपर मिल की हुई, वही हालत दरभंगा स्थित मिथिला विश्वविद्यालय व संस्कृत विश्वविद्यालय की भी है। पूरे देश में दरभंगा ही एक ऐसी जगह है, जहां एक परिसर में दो-दो विश्वविद्यालय चलते हैं, पर ये दोनों विश्वविद्यालय सबसे लावारिस हालात में हैं। अधवारा नदी को लेकर भी बड़ी परेशानी है। योजना बनी थी कि इसे नियंत्रित किया जायेगा, पर आज तक लोग इंतजार ही कर रहे है।"

स्वार्थी राजनीति दरभंगा से जनता पार्टी के सांसद विजय कुमार मिश्र कहते हैं, "मिथिला के पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक दलों की स्वार्थपरक राजनीति है। मिथिला की बेहतरी के लिए कहीं कोई बेचैन नहीं। मिथिला में कांग्रेस का प्रभाव रहा है। हर कांग्रेस-सरकार ने अकसर मिथिला के साथ सिर्फ छल किया है। यहां तक कि मिथिला के इलाके में जितने सरकारी अधिकारी पदारूढ़ होते हैं, वे भी राजनीतिक गुटबाजी के आधार पर। नतीजतन, हर अधिकारी सिर्फ उस गुट के स्वार्थ को पूरा करने के लिए परेशान रहता है। मिथिला के विकास की चिंता भला वे क्यों करने लगे? कई साल गुजर गये, मैंने दरभंगा के तालाबों को दुरुस्त करवाने के लिए पंद्रह लाख रुपए फिशरीज डिपार्टमेंट से स्वीकृत करवा दिये थे, पर आज तक वे रुपए खर्च तक न हो सके। बिंदेश्वरी दुबे के राज में तो मिथिला का और भी तिरस्कार हुआ। यातायात का संकट भयावह है। हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया। रेल यातायात का सबसे कारगर माध्यम है। स्व० ललित नारायण मिश्र के प्रयास से लौकहा-लौकही और फारबिसगंज-भवटीयाही रेललाइन बनने का काम हुआ, पर दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी लाइन और सकरी हसनपुर छोटी रेल-लाइन अरसे से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक नहीं बन सकी है। फारबिसगंज-दरभंगा लेटरल रोड की योजना भी फंसी हुई है। उद्योग, विद्युत-आपूर्ति, यह सब मिथिला के लिए अलभ्य चीजें हैं। आखिर, कब तक मिथिला के हक से खेल होगा?"

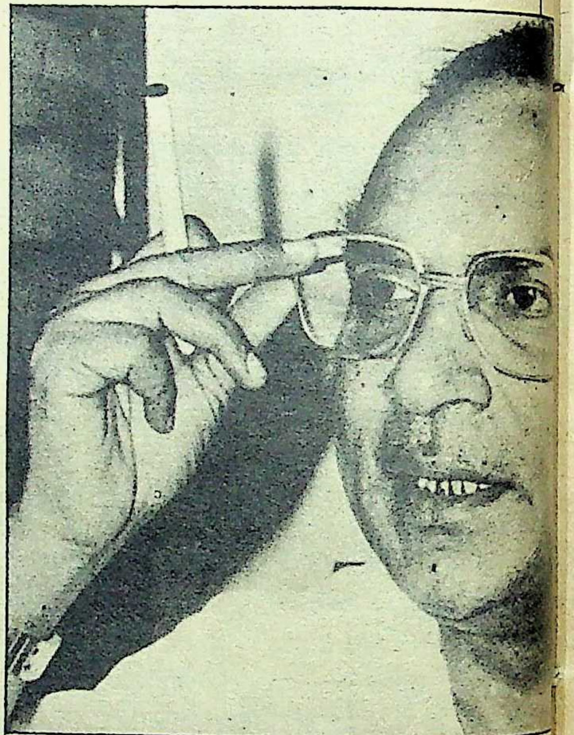

अपर्याप्त शिक्षा: विधायक कलीम अहमद

मिथिला मछली और मखान के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन मिथिला के मछुवारे सरकारी नीतियों के चलते, मछुवा समितियों में बड़े व्यवसायियों के कूद पड़ने से अपना यह पुश्तैनी पेशा लगभग छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। मिथिला के पोखरों में बड़े पैमाने पर होनेवाली मखान की खेती धीरे-धीरे खतम होती जा रही है। कारण, मखान के उत्पादकों को सरकारी स्तर से सुसंगठित व्यवसाय करने के लिए समुचित मदद नहीं मिलती है। नतीजतन, मिथिला की संस्कृति से जुड़ा 'मखान' धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है।

सामंती शोषण के विरुद्ध मिथिला में बस गिनती के ही संघर्ष हुए। १९६० के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सेली-बेली कांड हुआ था, पर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष में चूकती चली गयी। इधर 'इंडियन पीपुल्स फ्रंट' ने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश शुरू कर रखी है।

जल जमाव की समस्या से भी मिथिलावासी किसान कम तबाह नहीं हैं। सहरसा जिले की लगभग ४५ हजार हेक्टेयर भूमि में जल-जमाव का गहरा संकट है। केंद्रीय जल-आयोग के पास इस समस्या के निवारण हेतु प्रारूप भी भेजा गया है। पर तय है, आनेवाले वर्षों में भी कोसीवासियों की व्यथा का अंत नहीं होने वाला। प्रतिवर्ष कोसी के पूर्वी व पश्चिमी तटबंध के बीच बसी बड़ी आबादी तबाह होती है, पर उनका कोई पुरसाहाल नहीं।

मिथिला के विकास हेतु
दरभंगा-समस्तीपुर
हसनपुर रेल लाइन, निर्मली-भपटियाही रेल
विद्यापति सेवा संस्थान

रेल लाइन के लिए आंदोलन

चरमराता आर्थिक ढांचा : मिथिला की झोली में कुछ नहीं, सिवा हताशा और अपमान के। उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ उद्योग थे भी तो ठप्प हो गये। समस्तीपुर की 'ठाकुर पेपर मिल' बहुत पहले बंद हो गयी। 'अशोक पेपर मिल' भी बंद है। सरकार कई सालों से बस कोरा आश्वासन ही दे रही है कि इसे खुलवाया जायेगा। लगभग साढ़े सात करोड़ की लागत से बननेवाली प्रस्तावित समस्तीपुर की ग्लुकोज फैक्ट्री का काम १९८१ में शुरू तो हुआ, पर बाद में ठप्प पड़ गया। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार १९८१ में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर बना तो दिया गया, पर मात्र खुद इस प्राधिकार की स्थिति रुग्ण है। पंडौल में स्व० संजय गांधी ने दस करोड़ रुपए की लागत से बननेवाली स्पिनिंग मिल का शिलान्यास भी किया था, पर इस मिल की प्रगति भी शिथिल है। सहरसा जिले के बीरपुर में भी एक स्पिनिंग मिल बननी स्वीकृत हो गयी थी, पर बाद में उसे अस्वीकृत कर दिया गया। सुपौल में एक चीनी मिल, पूर्णिया में जूट मिल आदि बनाने की सरकारी घोषणाएं तो हुईं, पर हुआ कुछ नहीं। १९७६ में फारबिसगंज और किशनगंज में जूट मिल के लिए शिलान्यास तक हो गया, पर उसके बाद सब काम ठप्प पड़ गया। जाहिर है, मिथिला को सभी ने ठगा।

मिथिला को उद्योग नहीं मिले, सड़कें नहीं मिली, वहां पुल नहीं बने, बिजली का तो सवाल ही नहीं, शिक्षा भी मजाक ही हो गयी। सांस्कृतिक मरण की ओर भी मिथिला उन्मुख है। पहले दुसाधों के बीच लोक कथाओं के वीरनायक राजा सहलेस की पूजा होती थी, गांवों में दुसाधों की टोली में राजा सहलेस का मंदिर होता था, पर अब ये सब बातें भी लुप्त होती जा रही हैं। गांवों में मुसहरों के देवता 'दीना भद्री' का नाम भी सुनने को कहीं नहीं मिलता। घनश्यामपुर के विधायक महावीर कहते हैं, "राजा सहलेस या दीनाभद्री' जैसे ऐतिहासिक पात्रों की उपेक्षा मिथिला के उच्चवर्ग ने की। उसे अपने कार्यक्रमों में शरीक कर उजागर नहीं किया। नतीजतन, मिथिला के उच्च व निम्न वर्ग में पहले जो अनुराग था, उसमें कमी आयी है।"

सावन के महीने में राजा सहलेस की पूजा होती है। चाहे किसी भी जाति के लोग हों, इस मौके पर 'मनौती' मनाते हैं। गांवों में आज भी यह मान्यता है कि बैलगाड़ी अगर दलदल में फंस जाये या कोई संकट सामने उपस्थित हो, तो 'जय राजा सहलेस' कहकर आगे बढ़ने पर संकट से मुक्ति मिल जाती है। मिथिला में बाल-विवाह का आज भी बहुत चलन है, पर ज्यादातर छोटे तबकों में। मधुबनी से कुछ दूर सौराठ में प्रतिवर्ष लगनेवाली वैवाहिक सभा का भी आकर्षण मैथिलों में खतम हो रहा है। हां, पटना में 'चेतना समिति' संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विद्यापति पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम काफी धूमधाम से होता है। पहले यह आवश्यक था कि शादी करने जा रहा दूल्हा 'महफा' पर बैठकर शादी करने जाता जिसे कहार ढोकर ले जाता, पर नये समय का मिथिला का दूल्हा अब 'महफा' देखकर बिदक जाता है, महफा पर जाने की परंपरा अभी भी गांव के छोटे वर्ग में जीवित है।

यों, ऊपरी तौर पर मिथिला की प्रगति के सभी राजनेता चीखते हैं, पर मिथिला के लोग उसके पीछे की नीयत को अच्छी तरह समझते हैं। हाल में विधान सभाध्यक्ष शिवचंद्र झा का जगन्नाथ मिश्र से जब तनाव हुआ, तो उन्होंने एलान कर दिया था कि वह मिथिला की समस्या समझने के लिए मिथिला की पदयात्रा करेंगे। बस, इसी तरह की शह-मात के खेल में मिथिला विकास से कोसों पीछे होती जा रही है। मिथिला ने बहुतों को राजनीतिक शरण दी है। अब्दुल गफूर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, तो विधानसभाई चुनाव में अपने गृह जिले सिवान के बदले मधुबनी से आकर जीते। पर, जब अपने घर के लोग ही मिथिला की पीड़ा को नहीं समझे, तो गफूर-सरीखे आगंतुक क्या करते? डा० जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, राधानंदन झा, नागेन्द्र झा, शिक्षा मंत्री लोकेशनाथ झा, शिवचंद्र झा ऐसे अनगिनत राजनीतिक शूरमा मिथिला के हैं, पर इनका शौर्य मिथिला के किसी काम नहीं आया। मिथिला सबकी हुई, पर उसका कौन हुआ?

कौन बचायेगा मिथिला को, संवेदनशील लोग चिंतित हैं। वे बेचैनी से मिथिला के सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन की व्यथा महसूस कर रहे हैं। मिथिलावासी अपनी सांस्कृतिक पहचान से ही जाना जाता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं। सब कुछ चुक रहा है। कौन लड़ेगा, मिथिला के अस्तित्व की लड़ाई? राजनीतिक व आर्थिक लड़ाइयां तो देर-सबेर लड़ ली जायेंगी, पर संस्कृति को जीवंत रखने की लड़ाई कौन शुरू करेगा? सचमुच मिथिला को सपने में भी सुख नसीब नहीं।

■

छाया: अमरेन्द्र दुबे

ऐसी हैं मैथिल ललनाएं !

अनेक नदियों के जल में फंसी मिथिला जहां एक ओर बाढ़ की विभीषिका से सदैव पीड़ित रही है, वहीं कोमल उर्वरा मिट्टी की स्वामिनी भी रही है। इस कोमल मिट्टी से जन्म लेनेवाली मिथिला की स्त्रियां अकसर कोमल भाव रस-पूर्ण, सहज आप्लावित किस्म की हुआ करती हैं। वर्णाश्रम के अनुसार बंटी मिथिला की स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग श्रमिक स्त्रियों का है, जिनका काम पुरुषों का हाथ बंटाना है। उच्च वर्ग की स्त्रियां सामान्य गृह-कार्य से फारिग होकर कला के प्रति उन्मुख रही हैं। अभी भी मिथिला ही ऐसा क्षेत्र है, जहां स्त्रियां कपास के बीज डालने से लेकर रूई निकालने, पूनी बनाने तथा लकड़ी की तकली पर कच्चा धागा तक निकालने का काम करती हैं। अब तक मिथिला की स्त्रियों ने जनेऊ के पवित्र कर्म को अक्षुण्ण रखा है और यह विरासत अपनी अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करती आ रही हैं। सींकी और मूंज की सामग्री बनाने का बड़ा जोर है। सावन-भादों में जब पूरी मिथिला जलाप्लावित रहती है तब 'कतरा' नामक झाड़ से सींकी और 'कास' नामक झाड़ से मूंज निकाल कर उनसे नाना प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं बनायी जाती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त सामाजिक चेतना का प्रसार करने वाली श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जब मिथिला की इन कन्याओं को देखा, तो चमत्कृत हो उठीं। उनके द्वारा ये कलाएं राष्ट्रीय फलक पर लायी गयीं।

मिथिला की स्त्रियां चित्रकारी में विशेष अभिरुचि रखती हैं। इनमें निम्नवर्ग की स्त्रियां 'गाबिस मिट्टी' और गोबर से ज्यामितिक डिजाइन बनाती हैं, तो उच्चवर्ग की स्त्रियां प्राकृतिक रंग, चावल-हल्दी के घोल तथा सिंदूर के संयोग से। चावल के घोल से बनायी गयी अनुपम कला कृतियों को 'अरिपन' की संज्ञा दी जाती है।

उड़ीसा से आये और फिर मिथिला के ही होकर रह गये अमर कलाकार स्व० उपेन्द्र महारथी के सद्प्रयासों से मधुबनी चित्रकला बहुप्रचारित हुई तथा मिथिलावासी तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री स्व० ललित नारायण मिश्र का प्रोत्साहन पाकर मधुबनी अनेकानेक लोगों की जीविका का साधन बनी। आज पांच सितारा होटलों से लेकर विदेशों तक में मधुबनी चित्रकला की धूम है, पर मधुबनी चित्रकला के कलाकारों की स्थिति अभी भी दयनीय है। भारत सरकार ने जगदंबा देवी और सीता देवी आदि को पद्मश्री से सम्मानित भी किया। मिथिला में अपनी शैली की टेराकोटा आर्ट की भी परंपरा रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में भाई-बहनों के बीच खेली जानेवाली नृत्य नाटिका 'श्याम-चकेबा' होती है। चैत्र मास में 'घाटो' का खेल होता है। अभी तक इस कला को व्यावसायिकता ने नहीं घेरा है। बांस के बने बरतन-चुमाओन का डाला, मेघडंबर, साजी, चंगेरा आदि मैथिल महिलाएं अद्भुत बनाती हैं। साथ ही सींक की पंखी, तश्तरी आदि भी बनाती हैं, गांव की स्त्रियां। कपसिया-लोहा की एक मैथिल महिला द्वारा सूत से बनायी गयी चादर कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सर्वोत्तम ठहरायी गयी थी।

लोकगाथायें, संगीत और वाद्य का यहां की परंपरा में विशेष स्थान है। लोकगीत में अकसर शास्त्रीय शैली की झलक रहती है। स्त्रियां अपना सुख, अपना दुःख, अपनी पीड़ा, अपना उल्लास सब लयबद्ध गीतों के माध्यम से प्रकट करती हैं। गीत और लयबद्धता उनके जीवन का अंग हैं। ब्राह्म मुहूर्त्त 'प्राती' से लेकर सोने के समय के 'महेशवाणी' तक स्त्रियां संगीत में जीती हैं। जीवन के विभिन्न अवसरों, वर्ष की छहो ऋतुओं एवं काल-सीमा का व्यतिरेक मैथिल-नारियों को नहीं भाता। कथनी है—'सांझ पराती, भोर बसंत, तखनई बूझ गीतक अंत, अर्थात शाम को प्राती, भोर को बसंत राग गाया तभी समझ लें गीत का अन्त हो गया।

सम्पूर्ण बिहार के स्तर पर पटना में एक महिला संगठन है, 'मैथिली महिला संघ'। इस संगठन का व्यापक उद्देश्य है, मिथिला की स्त्रियों का सामाजिक और शैक्षणिक पुनरुद्धार।

मिथिला के इतिहास में रानी लखिमा देवी और विश्वास देवी ने राजकाज बड़ी कुशलता से संभाला था। भारती देवी के शास्त्रज्ञान को कौन नहीं जानता ? सामान्य स्त्रियों के कला-कौशल के बल पर मिथिला चल रही है, बस, आवश्यकता है तो अपने आप को पहचानने की।

धर्म और संस्कृति की लीक पर चलती हुई मिथिला की स्त्रियों की आराध्य देवी पार्वती-गौरी हैं। जगज्जननी जानकी सीता को अपनी बेटी मान यहां की स्त्रियां दर्द झेलती हैं। अकाल की दरार से उपजी जानकी की तरह दुःसह दुख सह कर मर-मिट जाने का अहं पालती हैं मैथिल स्त्रियां।

मिट्टी, भाषा और कला का स्त्रीलिंग होना, तथा मिथिला के निर्माण से विकास तक की यात्रा में इनकी अहम भूमिका होना मात्र संयोग नहीं, एक ध्रुव सत्य है। मिथिला भूमि अभी भी शिला तुल्य 'अहिल्या' है, जब तक वह अपनी पहचान का आकार ग्रहण नहीं करती, समय की धारा बिलकुल किनारे से निकल जायेगी।

—उषा किरण खान

राजा सलहेस का मंदिर

छाया : अमरेंद्र दुबे

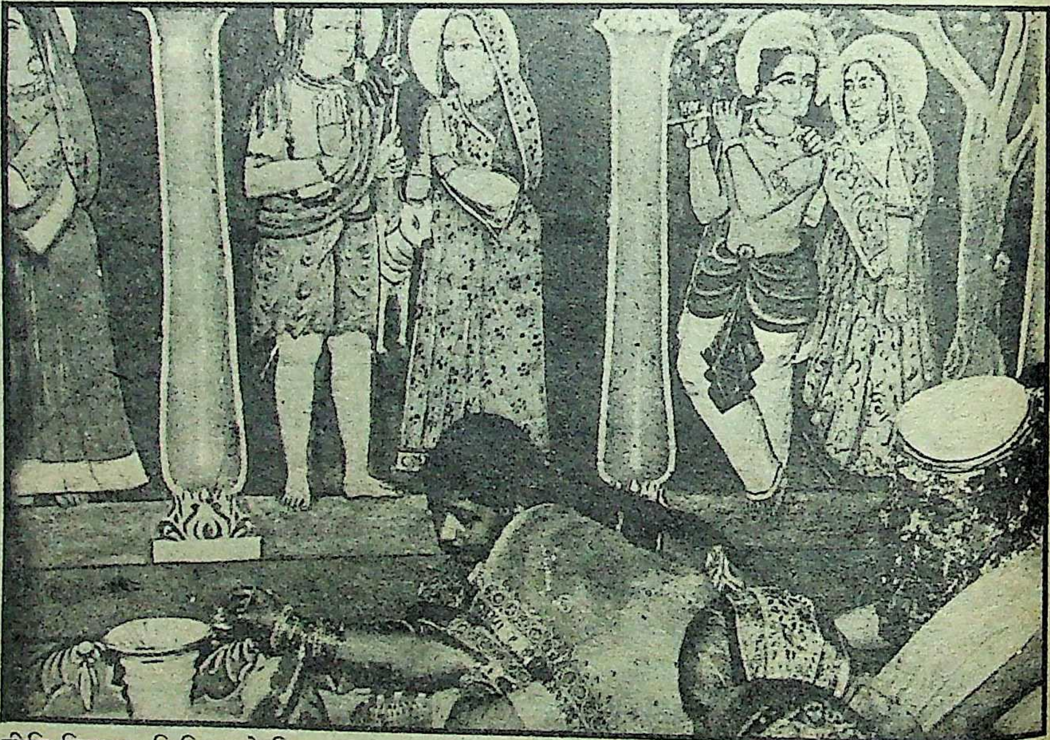

रीति-रिवाज : मिथिला के विवाह का एक दृश्य

मध्य प्रदेश में भी 'खतरे की घंटी'

अधर में: मोतीलाल वोरा

मध्यप्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखनेवाले एक नेता ने जुलाई के शुरुआती दिनों में 'माया' संवाददाता के कान में फुसफुसाकर कहा—"बास वापस आ रहे हैं।" बास से उनका अभिप्राय वर्तमान केंद्रीय संचार मंत्री अर्जुन सिंह से था। इन्हीं दिनों दिल्ली दरबार के मिज़ाज से वाकिफ़ और अर्जुन सिंह के करीबी एक सांसद से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी दृढ़ता से, करीब-करीब 'दावे' के अंदाज़ में कहा कि अर्जुन सिंहजी को फिर मध्यप्रदेश वापस भेजा जा रहा है। कारण और औचित्य के संदर्भ में उनका कहना था कि हरियाणा में पराजय से प्रधानमंत्री को यह अहसास हो गया है कि ऐन चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री बदलने से कुछ होगा नहीं। अर्जुन सिंह वापस जायें यां न जायें, लेकिन दिल्ली दरबार इस बारे में एकमत है कि वोराजी 'ढीले मुख्यमंत्री' हैं और उनकी ढिलाई से प्रशासन चौपट हो गया है। अगर उन्हें अभी से नहीं हटाया गया, तो चुनावी झंझावात में कांग्रेस-इ की नैया मुश्किल से पार लगेगी। राजधानी भोपाल में इन दिनों किसी भी राजनीतिक लाबी के सदस्य से बातचीत क्यों न की जाये, बातचीत में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के भविष्य को लेकर अटकलों का समावेश जरूर होगा। और तो और, इन दिनों वोरा-सरकार के मंत्री और उनके 'कॉकस' के सदस्य तक वोराजी के 'टिकाऊपन' को लेकर आशंकित हैं। सबका कहना है कि वोराजी का पत्ता कटने के 'फिफ्टी-फिफ्टी' चांस हैं। हो सकता है कि वोराजी अभी हटाये जायें या फिर कुछ महीनों की मोहलत के बाद।

शिविर में दरार: पूर्व मुख्यमंत्री मसलन श्यामाचरण शुक्ल, प्रकाशचंद सेठी और अर्जुन सिंह की तुलना में वोरा के पास लाबी जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन दो ढाई सालों में ले दे कर वोरा का अपना जो गुट या काकस तैयार हुआ है, उसमें भी अब दरारें पड़ गयी हैं। सबसे उल्लेखनीय प्रसंग गृह राज्य मंत्री कैप्टन जयपाल सिंह और राज्य उद्योग मंत्री माणक अग्रवाल का है। दोनों नेताओं के मध्य झगड़ा रायपुर में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों के दरम्यान हुआ। हुआ यह कि कैप्टन और माणक में प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम में मंजर भोपाली के गीत को शामिल करने को लेकर तकरार हो गयी। बाद में बात तू तू-मैं मैं तक पहुंच गयी और दोनों ने एक दूसरे को 'देख लेने' तक की धमकी दे डाली। राज्य मंत्री विट्ठल भाई पटेल और पूर्व मंत्री विजय पाटनी के बीच-बचाव से किसी तरह मामला सुलझा। बताते हैं कि इस मामले में विट्ठलभाई ने अपने सहयोगी मंत्री कैप्टन जयपाल सिंह का पक्ष लिया और माणक की शिकायत मुख्यमंत्री से की। दोनों मंत्री इस कदर क्षुब्ध थे कि उन्होंने २१ जून को रायपुर में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी काबीना की बैठक में भी भाग नहीं लिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि इन नेताओं में आपस में बोलचाल बंद है।

मंत्रियों की छवि: वोरा सरकार के कुछ मंत्रियों की छवि दिनोंदिन धूमिल होती जा रही है। इस सूची में अग्रणी हैं, वित्त एवं पृथक आगम मंत्री राम किशोर शुक्ल। "अपने पुत्रों का अमंगल भला क्यों चाहूंगा," का उद्घोष करनेवाले शुक्ल इन दिनों बीमार और अशक्त हैं। वह स्मृति-लोप के भी शिकार हैं। मगर उनका नसीब कि वोराजी मुख्यमंत्री हैं। नतीजतन शुक्लाजी कुर्सी पर जमे हैं। मंत्री महोदय पुत्रों का अमंगल भले ही न चाहें, लेकिन बेटों की करतूतों से पिता का अहित जरूर हो रहा है। शहडोल ज़िले के ब्योहारी में सर्कस के तंबू में मंत्री के पुत्रों के हुड़दंग करने और गोलियां दागने की घटना से वित्तमंत्री और सरकार दोनों की भद्द हुई है। राज्य विधान सभा में ९ जुलाई को विपक्ष ने इस मामले को उठाया। जनता पार्टी के प्रेमलाल मिश्रा ने बारंबार कहा कि आरोपियों में मंत्री-पुत्रों का नाम है। विपक्ष का आरोप है कि शुक्ल के बेटों—विनोद और संतोष ने सर्कस में हुड़दंग व मारपीट की, लेकिन सरकार है कि मंत्री के बेटों को बचा रही है। विपक्ष का क्रोध इस बात को लेकर भी है कि वित्तमंत्री दो दिनों बाद शहडोल गये और कलेक्टर को छुट्टी पर जाने को कह दिया। विपक्ष के नेता कैलाश जोशी ने यहां तक कहा कि सच्चाई जानने के लिए कलेक्टर को सदन में बुलाया जाये। उल्लेखनीय है कि मंत्री के पुत्रों पर पूर्व में भी मारपीट करने और इलाके में आतंक बरपाने का आरोप लग चुका है। कतिपय सूत्रों का कहना है कि मंत्री-पुत्रों ने ब्योहारी में गड़बड़ी के बाद भोपाल आकर अपने पिता के सरकारी आवास 'विंध्य कोठी' में शरण ली, इस संबंध में चर्चा के लिए 'माया' संवाददाता ने शुक्ल से संपर्क करना चाहा, लेकिन हर बार उनके पी०ए० से ही बातें हुईं और कोई नतीजा नहीं निकला। हाल में, जिस एक और मंत्री के दामन पर गंभीर आरोप का दाग लगा है, वह हैं वोरा सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री भारत सिंह। पांच जुलाई को रतलाम में भाजपा कार्यकर्ता सुंदरलाल मोगरा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। सुंदरलाल पटवा समेत अनेक भाज़पा विधायकों ने सदन में कहा कि मोगरा की हत्या सिंह के इशारे पर हुई है और वह अब हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। मोगरा ने पिपलौदा की शराब की दुकान के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा था। यह दुकान भारत सिंह के मित्र सुरेश जाट की बतायी जाती है। रतलाम के पूर्व जिलाधीश जैमिनी शर्मा ने इस दुकान का ठेका निरस्त कर दिया था। इस पर सिंह ने शर्मा का तबादला करा दिया। नये जिलाधीश आये, तो उन्होंने जाट को फिर से ठेका दे दिया। मोगरा ने जब विरोध ज़ारी रखा, तो उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर इस कदर तीखे हमले किये कि मुख्यमंत्री वोरा की हत्याकांड की गुप्तचर जांच कराने की घोषणा करनी पड़ी। इस बारे में 'माया' ने जब उद्योग मंत्री भारत सिंह से संपर्क साधा, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेषवश उनपर हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता चाहें, तो वहां जाकर जांच कर सकते हैं। यदि जांच में वह दोषी पाये गये, तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। वोरा सरकार के एक अन्य मंत्री के पुत्र पर पिछले दिनों एक हरिजन महिला से बलात्कार का आरोप लगा है। भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने के आरोपों से तो कई मंत्री बिंधे हुए हैं। वोरा के गृह नगर दुर्ग के वासी और म०प्र०खनिज निगम के अध्यक्ष रामानुज लाल यादव इन दिनों अपनों को उपकृत करने और अपने रंगीले मिजाज के कारण खासे चर्चित हैं। अपनी गहन और व्यापक गतिविधियों के कारण वोरा के बंधु बांधव भी चर्चाओं के घेरे में हैं।

आगामी कल: सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री मोती लाल वोरा इस मायने में बदनसीब हैं कि वह जबसे मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं और हड़तालों की चपेट में है। वर्षा की कमी के कारण प्रदेश सूखे और अकाल की देहरी पर है। प्रदेश में हरिजन-आदिवासियों और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं थमी नहीं हैं। ताजा मिसाल सागर से १७ किमी० दूर कर्रापुर की है। कर्रापुर के ३५ वर्षीय हरिजन मिहीलाल को पुलिस ने हवालात में लात-घूंसों और डंडों से इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गयी। मिहीलाल का अपराध यह था कि वह पुलिस के चंगुल से मुक्ति के लिए दो हजार रु० की रिश्वत का बंदोबस्त नहीं कर सका था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली की रैली में २० सूत्री कार्यक्रम में उपलब्धियों के लिए मोतीलाल वोरा की पीठ ठोंकी थी, मगर अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि वोरा ने वाहवाही फर्जी आंकड़ों के बल पर लूटी थी। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने वोरा को 'चैलेंज' किया है कि वह केंद्र को भेजी रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराकर कथित उपलब्धियों का प्रकट सत्यापन करा लें। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर अमल और उनकी जानकारी के लिए वल्लभ भवन में प्रधानमंत्री प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है, किंतु इस प्रकोष्ठ की हैसियत सिर्फ होने भर की यानी नाममात्र की है। और तो और, प्रधानमंत्री के निर्देशों पर अमल में भी खोट है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सरगुजा जिले में कठबोड़ो में सरपंच राधेश्याम यादव के अनुरोध पर परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू की थी, लेकिन वह चार दिन बाद ही बंद हो गयी। देवीगढ़ में एक आदिवासी को प्रधानमंत्री ने उससे ली गयी रिश्वत की राशि वापस कराने का आश्वासन दिया था, मगर वह रकम उसे आज तक वापस नहीं मिली है। जानकार सूत्रों के अनुसार, यह शिकायत आलाकमान से प्रदेश के अनेक सांसदों ने की है कि उनके परामर्श, अनुशंसा और आग्रह की कोई कद्र नहीं है और उन्हें 'रद्दी की टोकरी' में डाल दिया जाता है। प्रदेश के अनेक विधायक पावस सत्र के बाद दिल्ली जाकर आलाकमान को परिस्थितियों से अवगत कराने का 'मूड' बना रहे हैं। आम धारणा है कि वोरा चुनाव के लिहाज से अक्षम नेता हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि आलाकमान मध्यप्रदेश के बारे में जल्द ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले डाले।

सुधीर सक्सेना

सिद्दीकी बनाम सिद्दीकी

वोरा-सरकार में दो दर्जन विभागों के राज्य मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी और भाजपा से इंका में आये हसनात सिद्दीकी के बीच राजनीतिक तकरार के क्या कारण हैं? दोनों सिद्दीकियों के बीच खींचातानी का दुष्परिणाम क्या हो सकता है?

अर्जुन सिंह लाबी से खतरा : रसूल अहमद सिद्दीकी

हालांकि, दोनों ही नेता, जाहिरा तौर पर इनकार करते हैं, लेकिन अंदरूनी सच्चाई यह है कि दोनों में भीतर-ही-भीतर बेतरह ठनीं हुई है। एक ओर हैं, वोरा-सरकार में करीब दो दर्जन विभागों के राज्य मंत्री रसूल अहमद सिद्धीकी और दूसरी ओर कल तक भारतीय जनता पार्टी और आज सत्तारूढ़ इंदिरा कांग्रेस के विधायक हसनात सिद्धीकी। सिद्धीकी बनाम सिद्धीकी के इस द्वंद्व में दोनों ओर से तरह-तरह के पैंतरे और दांवपेंच आजमाये जा रहे हैं। रसूल मियां वर्तमान मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के मंत्रिमंडल के सदस्य ही नहीं, उनके विश्वासपात्र और नजदीकी सलाहकार भी हैं। दूसरी ओर, हसनात भी अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इंका के शिविर में वह अचानक या अपने अकेले के दम पर नहीं आये हैं। विधायक पद को त्याग कर फिर से जनादेश लेने के जोखिम के पीछे एक सुनियोजित व सुविचारित रणनीति काम करती रही है और प्रदेश का सबसे मजबूत और बड़ा राजनीतिक गुट उनके पीछे सक्रिय है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जेल पंचायत, वक्फ, उर्दू अकादमी आदि विभागों के मंत्री रसूल अहमद सिद्धीकी वोरा-सरकार में भोपाल के अकेले नुमाइंदे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि रसूल मियां को यह पद सेंतमेंत नहीं मिला है। पिछले चुनाव में भोपाल में इंका की लाज रखने का गौरव उन्हें मिला था, अन्यथा बाकी तीनों सीटों पर भाजपा ने इंका को पटखनी दे दी थी। और तो और, स्वयं हसनात सिद्धीकी तब भाजपा के टिकट पर दक्षिण भोपाल से इंका उम्मीदवार को हराकर विजयी हुए थे। अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में रसूल अहमद की गिनती श्रीनिवास तिवारी, राणा नटवर सिंह, राधेश्याम शुक्ल आदि के साथ असंतुष्टों में हुई। अर्जुन सिंह ने असंतुष्टों को संतुष्ट करने की मुहिम में घाटे के निगमों के जरिये मुनाफे की राजनीति का दांव खेला, तो उन्होंने निगम में पद ठुकराकर सिंह का दांव उलट दिया था। स्पष्ट है कि इसके बाद से अर्जुन सिंह का गुट सिद्धीकी को अपने राजनीतिक बैरियों में गिनने लगा। सिंह के भोपाल से चंडीगढ़ जाने के बाद, जैसा कि स्वाभाविक था, रसूल मियां के दिन बहुरे। मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सिद्धीकी को मंत्री बनाया। रसूल सिद्दीकी के मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने से सिंह-गुट की व्यथा बढ़ी हो, तो ताज्जुब नहीं। सिंह-गुट को सिद्दीकी दिनोंदिन और ज्यादा इस नाते खटकने लगें, क्योंकि वोरा ने अनेक राजनीतिक निर्णय, जानकार सूत्रों के अनुसार, सिद्दीकी की सलाह पर लिये। मांणक अग्रवाल को राज्य उद्योग निगम में अध्यक्ष और शिखरचंद जैन को भोपाल विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष-पद दिलाने में सिद्दीकी की अहम भूमिका रही। भोपाल में सत्ता के गलियारों में आज जब कभी राजनीतिक समीकरणों की चर्चा होती है, तो सिद्दीकी, माणक और शिखर जैन की चर्चा 'तिकड़ी' के तौर पर एक साथ होती है।

आरोपों के घेरे में : पिछले दिनों दिल्ली के अखबारों में राज्य मंत्री महोदय से संबंधित इस आशय की खबर चटखारे लेकर पढ़ी गयी कि रसूल सिद्दीकी के खिलाफ धनिये में मिलावट को लेकर वारंट जारी हुआ था। किस्सा यह बताया जाता है कि १९७३ में भोपाल

नगर निगम के खाद्य अधिकारी ने रसूल सिद्दीकी के होटलमेट्रो से पिसी धनिया का जो नमूना जब्त किया था, वह मिलावटी था। इस सिलसिले में निगम ने बाद में होटल मालिक के खिलाफ अदालत में मामला भी दाखिल किया था, लेकिन बाद में मामला दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

रसूल अहमद सिद्दीकी पर जहां धनिये में मिलावट का आरोप है, वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी हसनात सिद्दीकी हत्या के आरोप के शिकार हो चुके हैं। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राघवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह की हत्या के आरोप में जो चौदह व्यक्ति गिरफ्तार हुए और जिनके खिलाफ चालान प्रस्तुत किया गया, उनमें हसनात सिद्दीकी भी एक थे।

सिद्दीकी बनाम सिद्दीकी का द्वंद्व पिछले दिनों रमजान के महीने में रंग लाया। शहर काजी की ईद को सादगी से मानने की अपील का इस्तेमाल मुस्लिम कौंसिल ने अपने तरीके से किया और जमकर परचेबाजी की। एम०पी० मुस्लिम कौंसिल के संयोजक 'इंपीरियल सेब्रे' होटल के मालिक जनाब सईद खां हैं और अन्य लोगों के अलावा हसनात सिद्दीकी भी इसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सईदुल्ला खां ने 'माया' से कहा, "मुस्लिम कौंसिल के गठन में रत्तीभर राजनीति नहीं है और न ही इसके पीछे कोई राजनीतिक लाबी सक्रिय है।" ऐसा प्रतीत होता है कि सईद मियां यह बात महज सद्भावनावश कह रहे हैं, क्योंकि कौंसिल के परचे में यह कहा गया है कि कौंसिल एक बिलकुल अराजनीतिक संघ है, परंतु जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने की पूरी चेष्टा करेगी। कौंसिल से संबद्ध लोग यह स्वीकार करने में हिचकते नहीं कि उन्होंने कौंसिल की ओर से रोजा अफ्तार विशेष तौर पर उस दिन रखा, जिस दिन रसूल अहमद सिद्दीकी ने अफ्तार का प्रबंध किया था। सईद मियां के मुताबिक कौंसिल ने रोजा अफ्तार के भोपाल में करीब बीस कार्यक्रम आयोजित किये और हरेक प्रोग्राम में दस से बीस हजार लोगों ने भाग लिया। हालांकि, संयोजक महोदय बाहरी मदद से इनकार करते हैं, लेकिन एक वर्ग की धारणा है कि रोजा अफ्तारों के प्रबंध के लिए बाहर से पैसा आया। यह भी खबर लगी कि अरब देशों से लौटे एक मुस्लिम व्यवसायी जो एक उद अखबार में कालम भी लिखते हैं, ने समूचे आयोजन और प्रबंध में अहम भूमिका निभायी। कहना न होगा कि समूचे आयोजन में हसनात सिद्दीकी भी बढ़चढ़ कर सक्रिय रहे।

कट्टरपंथी : मुस्लिम कौंसिल में हसनात सिद्दीकी की रुचि यकबयक जागृत हो गयी हो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे उनकी पारिवारिक व इतर पृष्ठभूमि का हाथ है। बताते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि कट्टरपंथी मुफ्ती मुसलमानों की रही है। इनके पिता मुफ्ती इस्माइल सिद्दीकी मुस्लिम लीग से संबंद्ध रहे और इनके बड़े भाई सगीर बेदार जमायते इस्लामी के प्रतीक समाचार पत्र 'दावत' के संपादक रहे। उनका भाजपा छोड़ने का कारण भी शाहबानो के मसले पर भाजपा-नेताओं के रवैये से सहमत न होना बताया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिमायत में भोपाल के बुधवारा क्षेत्र में चारबत्ती पर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की गयी थी, उसमें हसनात सिद्दीकी ने भी शिरकत की थी। सभा में भाषण करते हुए उन्होंने ठेठ उस लहजे में प्रधामंत्री और कांग्रेस पार्टी को कोसा, जो सैयद शहाबुद्दीन जैसे नेताओं की पहचान बन चुका है। कामन सिविल कोड की खिलाफत करते हुए उन्होंने राजीव गांधी और कांग्रेसी राज को मुसलमानों का बैरी बताया था। उनके भाषण की एक बानगी यह है:

"हमारे नौजवान वजीरे आजम राजीव गांधी कहते हैं कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता। मेरी मां हिंदू थी, मेरा बाप पारसी था और मेरी बीवी रोमन कैथोलिक है। जो शख्स किसी मजहब को नहीं मानता, किसी मजहब की इज्जत नहीं करता, उससे यह उम्मीद करना कि वह सिर्फ मुस्लिमों के मजहब पर, शरीयत पर हमला कर चुप बैठ जायेगा नादानी की बात होगी।"

मंत्री बनने की आकांक्षा : हसनात सिद्दीकी

जहां तक हसनात सिद्दीकी का प्रश्न है, वह विनम्र हैं तथा अच्छे वक्ता भी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि यदि वह पारंपरिक कट्टरपंथी होते, तो वह भाजपा के कभी नजदीक नहीं जाते। हो सकता है उन्हें कट्टरपंथ की ओर इसलिए झुकना पड़ रहा हो, क्योंकि वह मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से बुरी तरह ग्रस्त हैं। निष्पक्ष आकलन करें, तो रसूल अहमद के रहते हसनात की यह महत्वाकांक्षा पूरी होना मुश्किल है।

अचरज की बात यह है कि वही हसनात सिद्दीकी आज भोपाल से इंदिरा कांग्रेस के विधायक हैं। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि हसनात को टिकट सिंह-गुट की मेहरबानी से मिला था, लेकिन उन्हें चुनाव जिताने में सभी गुटों का समान योगदान रहा। हसनात ने चुनाव में भाजपा के कोषाध्यक्ष और प्रभावशाली नेता कैलाश सारंग को कांटे की लड़ाई में करीब एक हजार मतों से परास्त किया था। सिद्दीकी जीत तो गये, किंतु अभी वह निश्चिंत नहीं हो सके हैं। कारण यह कि उनके प्रतिद्वंद्वी कैलाश सारंग ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनावी याचिका के जरिये सिद्दीकी के निर्वाचन को चुनौती दे रखी है।

सिद्दीकी बनाम सिद्दीकी के द्वंद्व के साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं। रसूल अहमद सिद्दीकी प्रारंभ से अड़ियल, तुनुकमिजाज व तेजतर्रार नेता रहे हैं। विभागीय अफसर भी उनकी डांट-डपट और लानत-मलामत करने की प्रवृत्ति से दुःखी रहे। लेकिन बीते साल पड़े दिल के गंभीर दौरे ने इन सब चीजों पर अंकुश लगा दिया है। म०प्र० शासन उन्हें हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए अमरीका भेजने पर विचार कर रहा है। उनके एक अत्यंत नजदीकी नेता के अनुसार—"इन दिनों रसूल मियां दुःखी हैं। एक तो शारीरिक अशक्तता और दूसरे हसनात मियां से तनातनी और पार्टी के विरोधी गुट द्वारा हमले पर हमले और लांछन। यह उनका दुर्भाग्य है कि पहले उन्हें हिंदू-विरोधी और मुस्लिमपरस्त घोषित किया गया और अब एक दूरगामी योजना के तहत उन्हें कट्टरपंथी तबका मुसलमान-विरोधी करार दे रहा है। बात एक हद तक सही है। मुस्लिम कौंसिल से अपनी कामयाबी मानती है कि मंत्रीजी को इस साल अपने घर पर आयोजित रोजा अफ्तार का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। बिरादरी में मंत्री सिद्दीकी पर तब भी उंगलियां उठी थीं, जब उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के साथ जाकर शंकराचार्य स्वरूपानंदजी का सत्कार किया था।

जहां तक हसनात सिद्दीकी का प्रश्न है, वह विनम्र हैं तथा अच्छे वक्ता भी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि यदि वह पारंपरिक कट्टरपंथी होते, तो वह भाजपा के कभी नजदीक नहीं जाते। हो सकता है उन्हें कट्टरपंथ की ओर इसलिए झुकना पड़ रहा हो, क्योंकि वह मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से बुरी तरह ग्रस्त हैं। निष्पक्ष आकलन करें, तो रसूल अहमद के रहते हसनात की यह महत्वाकांक्षा पूरी होना मुश्किल है। अगर किसी विधि रसूल मियां को गद्दी छोड़नी पड़े, तो हसनात के पौ-बारह हैं। ऐसी स्थिति में भोपाल के प्रतिनिधित्व के नाम पर हसनात सिद्दीकी का मंत्री बनना सौ फीसदी तय है। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना न बुरा है और न गलत। राजनीतिक लड़ाई में तरह-तरह के औजारों का इस्तेमाल भी जायज है, लेकिन जज्बात को भड़का कर उन्हें औजार बनाने का खेल आगे चलकर गुल खिला सकता है। बेहतर यह होगा राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक औजारों से लड़ी जाये और ऐसी हरकतों से बाज आया जाये, जिनसे भोपाल के बाशिंदों में नफरत और कटुता की भावनाओं को हवा मिलती हो।

—सुधीर सक्सेना

छाया: आर०सी० साहू

नाथद्वारा में हरिजन प्रवेश

भगवान के घर में राजनीतिक प्रदूषण

राजस्थान हरिजन सेवक संघ
- कार्यकर्ता सम्मेलन -
जिला शाखा - उदयपुर आपका
हार्दिक स्वागत करता है

हरिजनों के साथ अब भी ऐसा बरताव क्यों? : एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री जोशी

हरिजनों को हथकण्डा बनाकर राजस्थान के राजनेता किस प्रकार का घृणित राजनीतिक खेल खेलते हैं और बिना बात जातीय उपद्रव फैलाते हैं— इसका जीता-जागता उदाहरण है, नाथद्वारा में जून के अंतिम दिनों में घटी घटनाएं। मुख्यमंत्री जोशी चाहते थे कि हरिजन ढोल-धमाके के साथ श्रीनाथजी के मंदिर में प्रवेश करें, जबकि नाथद्वारा के कांग्रेस-इ के ही विधायक सी०पी० जोशी और विपक्षी नेता इसके खिलाफ थे। इससे नाथद्वारा में जातीय तनाव ने उग्र रूप धारण कर लिया। न केवल ढोल-धमाके के साथ हरिजन प्रवेश का आयोजन विफल रहा, बल्कि एक पूर्व सांसद और एक वर्तमान सांसद की नाथद्वारा की सड़कों पर पिटायी भी हो गयी। मुख्यमंत्री जोशी जातीय विद्वेष की आग फैलाने का कारण क्यों बन रहे हैं और विपक्षी नेता उस आग में घी क्यों डाल रहे हैं?

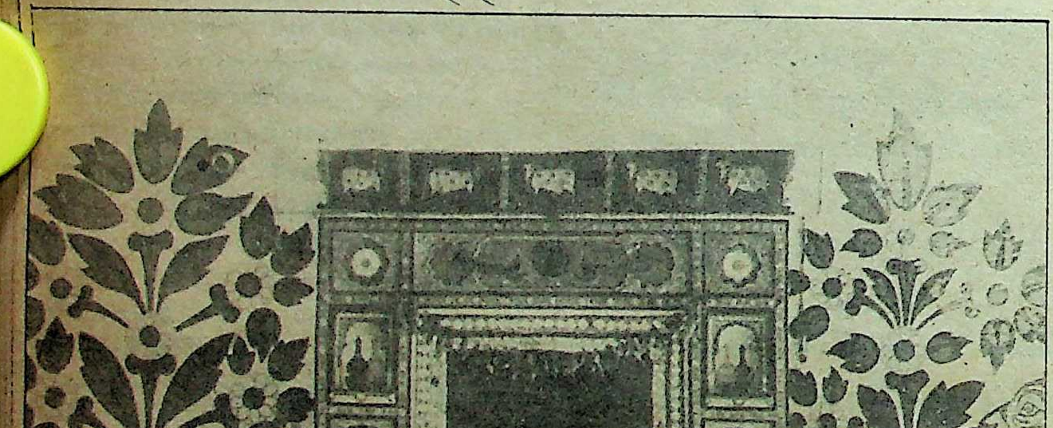

भगवान के घर में राजनीति क्यों? : श्रीनाथजी का प्रांगण

जयपुर में २०, २१ फरवरी को अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संचालक मंडल ने जब यह निर्णय लिया था कि राजस्थान हरिजन सेवक संघ के २९ जून को उदयपुर में होनेवाले वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रीनाथजी के मंदिर में घोषणापूर्वक हरिजनों का सामूहिक प्रवेश कराया जाये, तब उसे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि इससे कोई भारी बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। राजस्थान में नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां यद्यपि घोषित रूप से हरिजनों का प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरिजनों के लिए मंदिर के कपाट बंद हों। मंदिर-प्रवेश के नियमों का पालन करते हुए हर आदमी चाहे वह हरिजन हो या सवर्ण हिंदू या किसी भी धर्म का श्रीनाथजी भगवान के दर्शन कर सकता है। स्व० जगजीवन राम की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी, पूर्वमुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और श्रीमती शांति पहाड़िया को पूरे विधि-विधान से भगवान श्रीनाथजी के दर्शन कराये गये थे। मंदिर-मण्डल का लेखाधिकारी एक आदिवासी है और मंदिर-मण्डल के प्रशासक का सचिव ईसाई। मंदिर को सब्जियां और फल मुस्लिम वर्ग के लोग सप्लाई करते हैं। हरिजन सेवक संघ के संचालक मंडल को बंबई में रह रहे मंदिर के प्रमुख तिलकायत महाराज ने भी मंदिर के नियमों का पालन करने की शर्त पर हरिजनों के मंदिर प्रवेश की अनुमति दे

दी थी। नियम यह है कि मंदिर में प्रवेश के पूर्व हर दर्शनार्थी को तिलकायत महाराज द्वारा दी गयी कंठी और डोरा धारण करना होता है। राजस्थान हरिजन सेवक संघ के कुछ सदस्यों को इस शर्त पर एतराज था, पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गठित उपसमिति ने मंदिर की परपंराओं को सम्मान देने का निश्चय कर एतराज को रद्द कर मंदिर में हरिजन प्रवेश की तिथि ३० जून घोषित कर दी। राजस्थान हरिजन सेवक संघ के मंत्री प्रकाश गोयल के अनुसार तो तिलकायत महाराज ने संघ के कार्यक्रम को स्वीकृति देते हुए अपने पुत्र दाउजी को कंठी-डोरा वितरित करने का दायित्व निभाने के लिए नाथद्वारा भेजा भी था। इतना ही नहीं तिलकायत महाराज ने श्रीनाथजी मंदिर के मण्डल प्रमुख संतोष कुमार शर्मा को पत्र लिखकर हिदायत भी दी थी कि किसी वजह से उनके पुत्र दाउ बाबा नाथद्वारा न पहुंच सकें, तो उदयपुर में रहनेवाली उनकी बहन से कंठी-डोरा की रसम अदा करवायें। इस प्रकार श्रीनाथजी मंदिर में सामूहिक हरिजन प्रवेश का आयोजन तय करते समय किसी को किसी प्रकार के संकट का अंदेशा नहीं था, लेकिन २९ जून के कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के बाद से ही संकट के बादल घिरने लगे।

मुख्यमंत्री बनाम विधायक : 'हरिजन श्रीनाथ जी के मंदिर में समारोहपूर्वक प्रवेश करेंगे'—यह आयोजन हरिजनों को पटाने का एक अच्छा हथियार हो सकता है—संभवतः यही मानकर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इसका पुरजोर समर्थन करना शुरू कर दिया। और सरकारी स्तर पर इस आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जाने लगा। वह राजस्थान हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर नाथद्वारा के कांग्रेसी विधायक पी०सी० जोशी यह महसूस कर रहे थे कि यह आयोजन नाथद्वारा के आगामी चुनावों में उनकी पराजय का कारण बन सकता है। वह दूसरी बार यहां से विधानसभा चुनाव में विजयी हुए थे। पचास हजार की आबादीवाले नाथद्वारा में हरिजनों को निर्णायक वोट नहीं माना जाता। श्री जोशी के पूर्व इस सीट पर पहले जनसंघ फिर भाजपा का एकाधिकार रहा था। अतः जोशी ने इस आयोजन को अपने राजनीतिक हितों के विपरीत मानकर इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कंठी-डोरा धारण कर कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, ऐसे में सरकारी प्रचार-प्रसार से खामख्वाह आपसी कटुता को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी ओर 'माया' से मुख्यमंत्री जोशी का कहना था, "अगर हरिजन मंदिर में जाते ही रहे थे, तो फिर उन्हें समारोहपूर्वक जाने देने पर क्यों एतराज था।" विपक्षी नेताओं ने इस आयोजन में जोशी सरकार की दिलचस्पी को राजनीतिक चाल मानकर जोशी का समर्थन किया। इस प्रकार नाथद्वारा में इस मामले में जोशी सरकार हरिजनों के साथ थी, तो उनके ही विधायक (जोशी) और विपक्षी नेता इस आयोजन के खिलाफ थे। अतः नाथद्वारा में हरिजन राजनीति इस तिकोने चक्रव्यूह में फंस गयी थी। हरिजन सेवक संघ के सम्मेलन की तिथि २९ जून जैसे-जैसे निकट आने लगी वैसे-वैसे नाथद्वारा का जातीय-माहौल भी गरमाने लगा। श्रीनाथ जी मंदिर में हरिजनों के नाटकीय प्रवेश का सुनियोजित विरोध करने के लिए नाथद्वारा में सत्ताधारी कांग्रेस-इ सहित स्थानीय विपक्षी नेताओं ने एक संघर्ष समिति का गठन भी कर लिया। २९ जून को यहां राजस्थान हरिजन सेवक संघ का सम्मेलन होनेवाला था और माहौल यह था कि राज्य सरकार तो हरिजन संघ के साथ थी, लेकिन नाथद्वारा के पक्ष-विपक्ष सहित प्रायः सभी मंदिर-प्रवेश के आयोजन के खिलाफ थे। नाथद्वारा की संघर्ष समिति ने २७-२८ जून को 'नाथद्वारा बंद' का आयोजन किया। बंद सफल रहा, लेकिन हरिजन सेवक संघ की आंखें नहीं खुलीं और शांत नाथद्वारा में जातीय-विद्वेष का ज्वार उमड़ पड़ा।

उपद्रव : तय तो यह था कि राजस्थान हरिजन सेवक संघ का २९ जून को सम्मेलन हो जाने के बाद ३० जून को सम्मेलन में आये हरिजन सामूहिक रूप से नाथद्वारा जायेंगे और श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। २७ जून को हरिजन सेवक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं जनता शासन के पूर्व वित्तमंत्री मास्टर आदित्येंद्र नाथद्वारा जाकर श्रीनाथजी मंदिर के प्रमुख व अन्य गणमान्य लोगों से मिल आये थे। उन्हें वहां हरिजनों के मंदिर प्रवेश में पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला था, लेकिन राजस्थान हरिजन सेवक संघ ने हरिजन-प्रवेश का कार्यक्रम ३० जून के बजाय २९ जून कर दिया। नाथद्वारा के विपरीत माहौल को देखते हुए हरिजन सेवक संघ के नेता संभवतः सीधे संघर्ष को टालना चाहते थे और घोषित तिथि से एक दिन पूर्व मंदिर में 'हरिजन-प्रवेश' का कार्यक्रम सफल करके वे अपनी नाक भी बचाना चाहते थे, लेकिन वह अपनी नाक नहीं बचा सके। संघ के पचास कार्यकर्ता हरिजन सेवक संघ की अखिल भारतीय अध्यक्ष निर्मला देशपाण्डे के नेतृत्व में नाथद्वारा पहुंचे, लेकिन उन्हें स्थानीय संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के प्रबल विरोध के कारण मंदिर में प्रवेश किये बिना ही वापस उदयपुर लौटना पड़ा। उदयपुर में उसी दिन राजस्थान हरिजन सेवक संघ के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को जहां यह खबर मिली वहीं, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्रपाल सिंह का एक पत्र भी मिला जिसमें उन्होंने पहाड़िया दंपती और

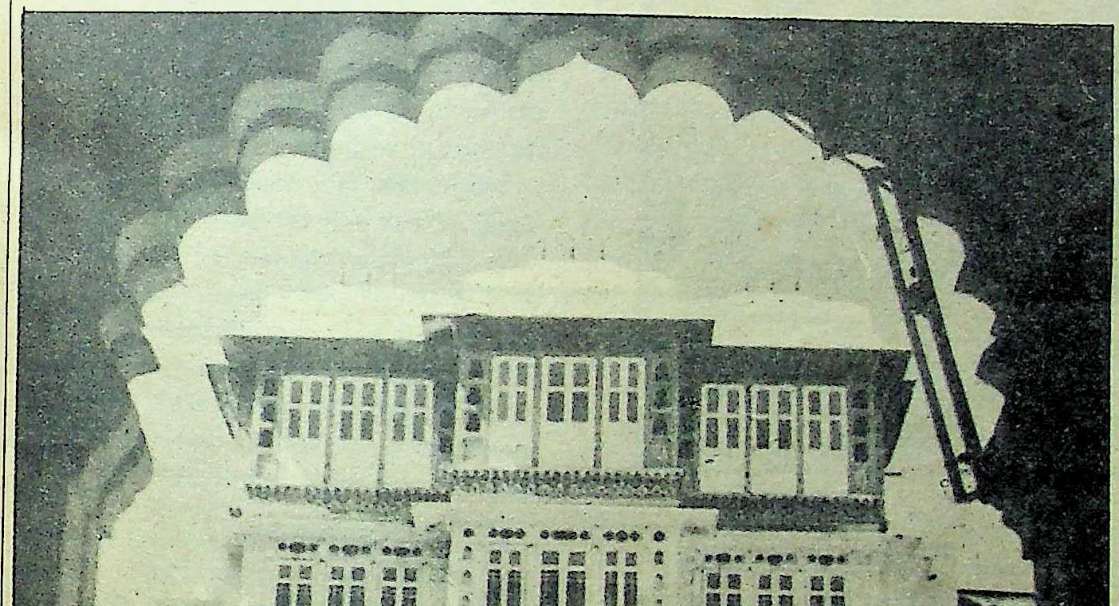

मोतीमहल : मंदिर प्रमुख तिलकायतजी का निवास

नाथद्वारा का श्रीनाथजी मंदिर

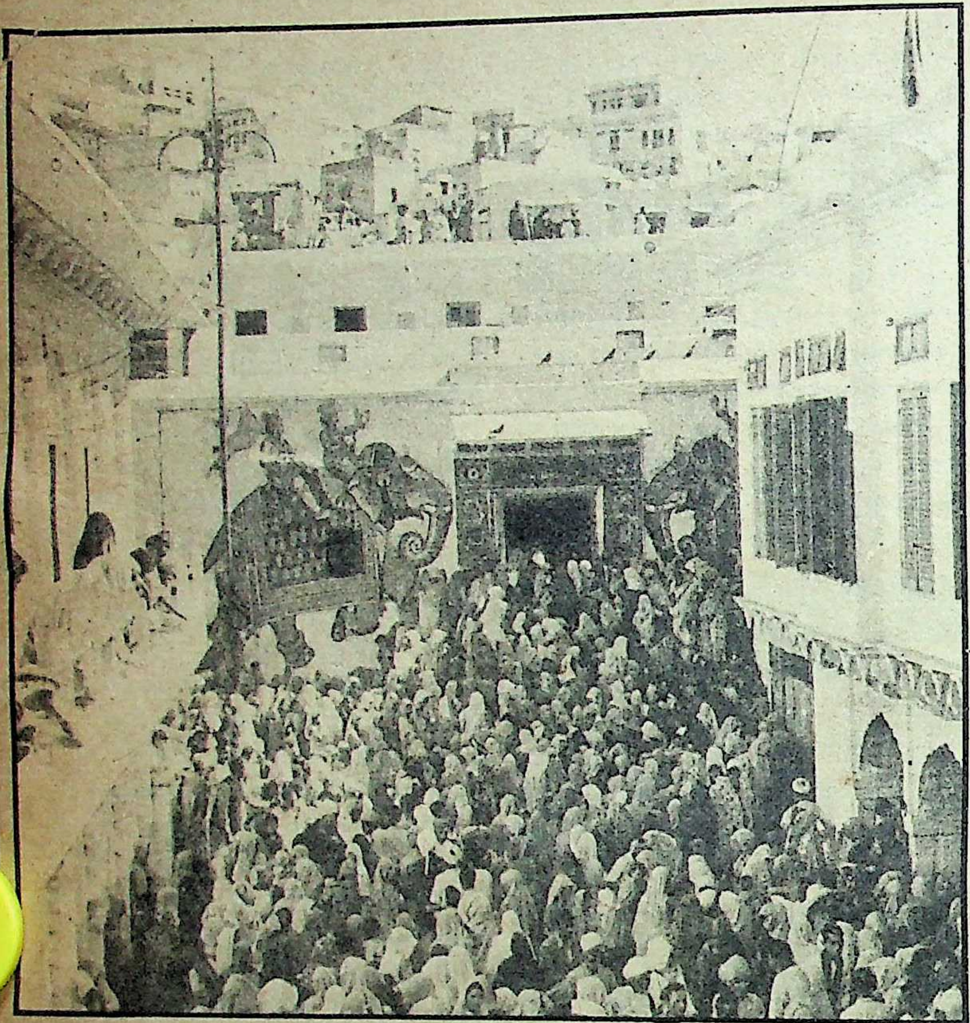

पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय की प्रधानपीठ नाथद्वारा में श्रीकृष्ण के बालस्वरूप की पूजा होती है। मंदिर की मूर्ति बारहवीं सदी की बतायी जाती है। १४९५ में वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना मथुरा के छोटे से मंदिर में की थी। १५१९ में इसे वहां से गोवर्धन लाया गया, जहां डेढ़ सौ वर्षों तक स्थापित रही। औरंगजेब ने जब मूर्तियां खण्डित करने का दौर चलाया तब वल्लभाचार्य के वंशजों ने मूर्ति के साथ मथुरा जिला छोड़ दिया। १६७१ में वह भटकते हुए राजपूताने में पहुंचे, यहां उन्हें मेवाड़ के राणा राजसिंह ने संरक्षण के साथ सियाद ग्राम में बसाया। मंदिर बनने और संरक्षण मिलने से यहां नाथद्वारा कस्बा बसा।

मंदिर के लिए सियाद ग्राम के चुनाव को लेकर कहा जाता है कि जब वल्लभाचार्य के वंशज मूर्ति रथ में सजा कर मेवाड़ की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे, तभी रथ के पहिये सियाद ग्राम की भूमि में बैठ गये। इससे समझा गया कि भगवान इसी स्थान पर रहना चाहते हैं। तब से श्रीनाथजी के मंदिर की हैसियत यहां एक रियासत जैसी बनी जो आज भी बरकरार है। मंदिर की सालाना आय ८० लाख से कुछ ज्यादा है। भक्तों की भेंट से यहां हर रोज आठ हजार रुपये का प्रसाद बनता है। यह खर्च तीस लाख रुपया प्रतिवर्ष आता है।

श्रीनाथजी के मंदिर को परम्परागत रूप में हवेली कहा जाता है और इस हवेली की दिनचर्या पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार संचालित होती है। हर रोज प्रातः पांच बजे मंगला की झांकी के साथ शुरू होनेवाली दिनचर्या सांयकाल शयन की आठवीं झांकी के साथ समाप्त होती है। इन झांकियों को दिनचर्या के अनुसार मंगला फिर शृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती व शयन कहा जाता है।

श्रीनाथजी की इस दिनचर्या का प्रबन्ध करने के लिए मंदिर में अलग-अलग महकमे बने हुए हैं, मसलन—कृष्ण भण्डार, खर्च भण्डार, गहनाघर, खासा भण्डार, प्रसादी भण्डार, समाधान, दूधघर, पानघर, फूलघर, सागघर, दर्जीखाना, परछना उस्तादघर, गुलाबघर आदि। इन भण्डारों में प्रसादी भण्डार, खर्च भण्डार, गहनाघर और खासा भण्डार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। खासा भण्डार में प्रत्येक भोग की सामग्री का चयन होता है। समाधान विभाग का समाधानी मुखिया हर वैष्णव की सेवा मंजूर करने का निर्णय करता है। वैष्णव भक्त से भेंट स्वीकार करने के सम्पूर्ण कार्य को समाधानी मुखिया अंजाम देता है। श्रीनाथजी के मंदिर में आनेवाले वैष्णव तरह-तरह की सेवा अर्पित करते हैं और हर सेवा का मूल्य निर्धारित होता है। मसलन, पूरे दिन की सेवा करनेवाले को तीन हजार पांच सौ रुपये देने होते हैं। एक सेवा का मूल्य १९६ रुपए, २५ पैसे होता है।

इस सेवा के अनुसार श्रीनाथ जी पर वैष्णव की ध्वजा चढ़ती है। ध्वजा के स्वरूप के अनुसार सेवा की लागत घट-बढ़ जाती है। मसलन यदि कोई वैष्णव रेशम व गोटे किनारी की ध्वजा फहराना चाहता है, तो सेवा का मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह की गोटा किनारी से हर वर्ष लगभग पचास किलो चांदी निकाली जाती है।

प्रतिवर्ष प्रसाद पर खर्च होनेवाले तीस लाख रुपए से हर माह पांच सौ पीपे घी, १२५ बोरी शक्कर, चालीस किलो बादाम और इतने ही काजू, पिस्ता, दाख, चिरौंजी आते हैं। सालभर में २५० ग्राम कस्तूरी और दस हजार क़ा अम्बर काम में आता है। हर रोज ४५० किलो दूध चढ़ता है, जिसके लिए छह लाख रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से एक गौशाला चलती है। हर रोज ६० क्विंटल लकड़ी का उपयोग इस प्रसाद को तैयार करने में होता है और साल में एक लाख रुपए की सब्जी प्रसाद के लिए तैयार की जाती है।

श्रीनाथजी के मंदिर में कार्य करनेवाले कर्मचारियों को नकद वेतन नहीं दिया जाता। वेतन के रूप में उन्हें हर रोज प्रसाद मिलता है। इस प्रसाद की मात्रा कर्मचारी के पद के अनुसार तय होती है। प्रसादी भण्डारी इसका बंटवारा करता है।
प्रसाद का बड़ा हिस्सा तिलकायतजी को हासिल होता है। कुछ प्रसाद मन्दिर में आनेवाले खास हैसियत के लोगों के लिए रखा जाता है और एक हिस्सा उन वैष्णवों को दिया जाता है जो विशेष भेंट चढ़ाते हैं।

श्रीनाथजी की सेवा में तीन तरह के कर्मचारी हैं जो सभी वंश परम्परा से नियुक्त होते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के कर्मचारियों में मुखिया और बाल-भोगिये आते हैं। इसके बाद सेवावाले और तीसरी श्रेणी में बृजवासी आते हैं। इनकी नियुक्ति और सेवा की श्रेणी बदलने का अधिकार तिलकायतजी को प्राप्त है।

हर रोज मिलनेवाले प्रसाद की मात्रा कर्मचारी की श्रेणी के हिसाब से होती है। इन्हे ४० रुपए से लेकर २५० रुपए मूल्य का प्रसाद रोज मिलता है जो बाजार में बिक जाता है।

अन्नकूट श्रीनाथजी का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पर एक लाख से ज्यादा वैष्णव दर्शन करने आते हैं। आदिवासी भीलों के लिए भी यह पर्व विशेष महत्व का होता है। इस दिन पके हुए सौ मन चावल इन्हें लुटाये जाते हैं। अन्नकूट के ३० दिन बाद छप्पन भोग का उत्सव होता है।

श्रीनाथजी के मंदिर के प्रबन्ध के लिए मंदिर मण्डल गठित है, जिसकी देखरेख के लिए सरकार की ओर से प्रबन्धक नियुक्त होता है, परन्तु सेवा-पूजा की सारी व्यवस्था तिलकायतजी की आज्ञानुसार होती है।

—ओम सैनी

श्रीमती जगजीवन राम के मंदिर-प्रवेश का उल्लेख करते हुए कहा था कि ऐसे में प्रचार और समारोह के साथ हरिजनों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। उन्होंने पत्र में यह भी चेतावनी दी, "फिर भी आयोजन हुआ, तो डटकर विरोध किया जायेगा।" श्री जोशी बौखला उठे थे। उन्होंने अपने भाषण में यहां तक कहा, "आजादी के चालीस साल बाद भी अगर छुआछूत समाप्त न हुई, तो यह देश खतम हो जायेगा।"

अब यह स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के पूरे सहयोग और समर्थन के बावजूद राजस्थान हरिजन सेवक संघ श्रीनाथजी के मंदिर में समारोहपूर्वक 'हरिजन-प्रवेश' के मंसूबों को पूरा नहीं कर पायेगा। फिर भी ३० जून को संघ की अखिल भारतीय अध्यक्षा निर्मला देशपाण्डे सहित पांच लोग स्थितियों का जायजा लेने नाथद्वारा पहुंचे। उन्होंने वहां जो माहौल देखा, उसके हिसाब से यह निर्णय लिया कि माहौल ठीक होने पर मंदिर में हरिजन-प्रवेश का आयोजन किया जाये। इस पांच सदस्यीय दल के साथ गये अ०भा०ह०से० संघ के उपाध्यक्ष एवं सांसद केयूर भूषण त्रिपाठी तथा राजस्थान के पूर्व सांसद गणेश लाल माली नाथद्वारा के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करने के लिए रुक गये, शेष उदयपुर लौट गये।

सांसद पिटे: राजस्थान हरिजन सेवक संघ द्वारा निश्चित तिथियों में हरिजन-प्रवेश समारोह रद्द करने के साथ ही दो दिन से चला आ रहा नाथद्वारा-बंद भी अगले दिन समाप्त हो गया। जनजीवन सामान्य देखकर एक जुलाई को गणेशराम माली मध्य प्रदेश के सांसद केयूर भूषण त्रिपाठी के साथ श्रीनाथजी के मंदिर में दर्शन कर आये। उनसे यही गलती हो गयी। माहौल विपरीत देखकर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दर्शन के बाद जब दोनों लोग नाथद्वारा के मुख्य बाजार से लौट रहे थे, तभी उत्पाती लोगों ने शोर मचाया कि 'भंगी श्रीनाथजी के दर्शन कर आये। मारो सालों को।' गणेशराम माली ने समझाने की कोशिश की तो थप्पड़, मुक्कों की मार के साथ उनके कपड़े फाड़ डाले गये। किसी तरह भागकर ये लोग बाजार की उस दुकान तक पहुंचे, जहां पुराने कांग्रेसी एवं स्वतंत्रता सेनानी फतेहलाल बापू अपना व्यवसाय करते हैं। यहां उपद्रवकारियों को फतेहलाल बापू सहित स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने समझाया कि गणेशराम माली के साथ किसी हरिजन ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि साथ जानेवाले व्यक्ति ब्राह्मण जाति के लोकसभा सदस्य केयूर भूषण त्रिपाठी हैं। पर उत्पाती नहीं माने और मारपीट करने लगे। तभी किसी ने पुलिस को सूचित किया, तो स्थानीय थानेदार सुरेंद्र सिंह पांच-सात पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गये। थानेदार ने स्थिति बेकाबू होते देखकर श्री माली और श्री त्रिपाठी को दुकान के अंदर ले जाकर शटर बंद कर लिया। इस पर भीड़ ने आसपास से घास-फूस लाकर दुकान के शटर के पास रखा और उसमें आग लगा दी। थानेदार सुरेंद्र सिंह स्वयं भीड़ से बचने के लिए दुकान की सीढ़ियों से छत पर पहुंच गयें और वहा से पीछे की ओर नीचे छलांग लगा दी, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गयी। उन्हें पुलिसकर्मियों ने किसी तरह पुलिस चौकी पहुंचाया।

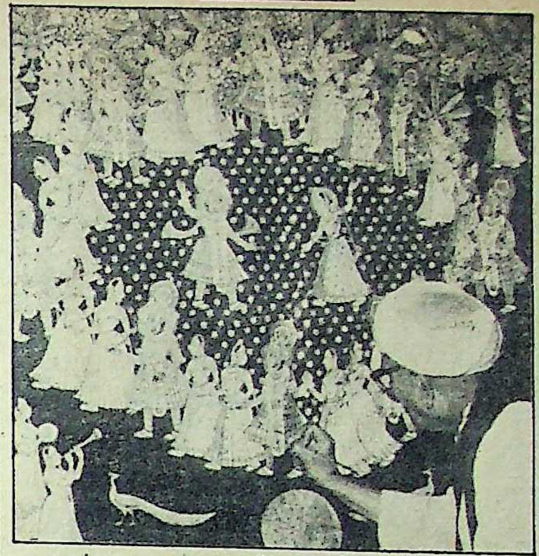

कला संसार : नाथद्वारा में रासलीला की चित्रकारी

लाला बाजार के नाम से मशहूर इस बाजार में बनी इस पुलिस चौकी को भी लोगों ने घेर लिया। उसे लूटा और सामान में आग लगा दी। पुलिस चौकी के बाहर जीप में जब लोग आग लगाने लगे, तो घायल थानेदार ने चार-पांच गोलियां चलाईं, जिनमें से एक, स्कूल से लौट रहे अध्यापक प्रहलाद राय की बांह में लगी। पुलिस ने अनेक लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी सूझबूझ से उपद्रव को नियंत्रित किया। लेकिन गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर नाथद्वारा और दो दिन बंद रहा। इन्हें बिना शर्त रिहा करने के लिए जिन नागरिकों ने घेराव और भूख-हड़ताल की धमकी दी, उनमें भाजपा और कांग्रेस-इ दोनों के नेता शामिल थे। गिरफ्तार लोगों को छोड़ देने के बाद ही नाथद्वारा में शांति स्थापित हो सकी।

उपद्रव की जिम्मेदारी: 'माया' ने पीड़ित सांसदों से कथा सुनी, तो पता चला कि उन पर तथा पुलिसकर्मियों पर मकानों की छतों से पत्थर मारे गये थे। एक जुलाई की सुबह शांत नजर आनेवाले नाथद्वारा में अचानक 'भंगी मंदिर हो आया' का शोर हुआ और दो हजार लोग आगजनी करने पर उतर आये। यह काम आनन-फानन में तभी हो सकता था, जब उनकी योजना पहले से बनी हो। निश्चित रूप से इस षड्यंत्र का अहसास उन लोगों को भी नहीं था जो इस आयोजन को हरिजन सेवक संघ की आड़ में मुख्यमंत्री द्वारा हरिजनों को पटाने की राजनीतिक साजिश करार दे रहे थे। बहरहाल, पूर्व जपाविधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र पाल सिंह नाथद्वारा की एक जुलाई की घटना के लिए पुलिस को दोषी नहीं मानते हैं, जबकि प्रदेश के गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं।

राज्य विधानसभा में विपक्ष एवं भाजपा के नेता भैरोंसिंह शेखावत तीन जुलाई को नाथद्वारा पहुंचे और वहां से लौटकर उन्होंने घोषणा की कि नाथद्वारा में हरिजनों के खिलाफ माहौल नहीं है। उनके अनुसार स्थानीय समस्याओं के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण जनता में पहले से रोष व्याप्त था। ऐसे में श्रीनाथजी के मंदिर में हरिजन प्रवेश की आडंबरपूर्ण घोषणा ने उन्हें और भड़का दिया। उनका मानना है कि इस समय हरिजनों में कांग्रेस-इ विरोधी भावनाएं जोर पकड रही हैं, जिन्हें मिटाने के लिए मुख्यमंत्री जोशी ने हरिजन प्रवेश की योजना बनायी, जिसका उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने विरोध किया है। उनका आरोप था कि बोहरा यूथ के लोगों ने कुछ समय पहले गलियाकोट में जियारत के लिए कूच किया था, जिन्हें इसी सरकार ने संरक्षण देने की जगह ताकत से दबाया था और आज वह ही हरिजन-प्रवेश का नाटक कर रही है। मुख्यमंत्री श्री जोशी से जब इस संदर्भ में 'माया' ने मुलाकात की तो उनका कहना था कि यह शर्मनाक बात है कि आज भी हम छुआछूत में यकीन रखते हैं।

कुल मिलाकर राजस्थान आज सांप्रदायिकता और जातीय झगड़ों को लेकर काफी संवेदनशील हो रहा है। सवर्ण और हरिजनों को लेकर पहला आंदोलन २ अक्तूबर, १९६१ में हुआ था। उस वक्त प्रदेश के सीकर जिले में स्थिति गणेशर नामक तीर्थस्थल पर समाजवादी नेता एवं जनता सरकार में उद्योग मंत्री रहे सूर्यनारायण चौधरी ने हरिजनों को स्नान करवाने में पहल की थी। इस पहल के परिणामस्वरूप दस हजार सवर्णों ने उन्हें मार-मार कर अधमरा कर दिया था। इस हादसे की चर्चा स्व० डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने तीन सितंबर, १९६३ में लोकसभा में की थी। तब और अब में केवल इतना फर्क हुआ है कि अब कानून हरिजन को संरक्षण देता है और हरिजन स्वयं अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हथकण्डे उनके हालात बद से बदतर बनाये हुए हैं।

वस्तुतः हरियाणा में कांग्रेस-इ की पराजय के बाद से प्रदेश के नये-पुराने नेताओं में द्वन्द्व शुरू हो गया है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही जिन पुराने नेताओं ने रामनामी परिवेश धारण कर लिया था, अब वे नयों के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर से निर्वाचित सांसद एवं कांग्रेस-इ महासचिव नवलकिशोर शर्मा ने पार्टी संगठन के चुनाव न होने पर नाराजगी प्रकट की थी। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से कांग्रेस में चल रहे तदर्थवाद के कारण पार्टी की छवि और विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा है। प्रदेश संगठन को निगाह में रखकर उन्होंने कटाक्ष किया था कि संगठन में कई लोग महत्वपूर्ण पदों तक घुसपैठ कर गये हैं। श्री शर्मा ने समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और प्रकोष्ठों के संयोजकों की फौज पर भी एतराज किया था। इसी अंदाज में पूर्वमुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और कई वर्षों तक चुप रहनेवाले सुखाड़िया मंत्रिमण्डल में वरिष्ठ मंत्री रहे मथुरादास माथुर ने फिर से राजनीति में सक्रिय होने की घोषणा कर दी है।

पुरानों की इन गतिविधियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद अशोक गहलोत के साथ-साथ मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को भी चौंकाया है। श्री जोशी को अब संगठन के युवा तुर्कों के साथ-साथ पुरानों की शतरंजी चालें भी पहचाननी पड़ रही हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आलाकमान के नये गठजोड़ परेशानी में डाल रहे हैं। शक और संदेह के इस वातावरण में नाथद्वारा में जो कुछ हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री समर्थक विधायक सी०पी० जोशी को और जोशी और उनके साथी मुख्यमंत्री को दोषी मान रहे हैं, जबकि इन हालात के लिए हमारा समूचा राजनीतिक परिवेश दोषी है, जो पिछड़े वर्गों के विकास के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वोटों के हिसाब से योजनाएं बनाता है या योजनाएं बनाने की मांग करता है।

—ओम सैनी

साक्षात्कार/सी०पी० जोशी विधायक नाथद्वारा

'परम्परा तोड़ने से लोग नाराज होंगे ही'

श्रीनाथ जी के मंदिर में हरिजनों के समारोहपूर्वक प्रवेश का वहां के कांग्रेस-इ विधायक सी०पी० जोशी ने विरोध किया। इस विरोध के परिणामस्वरूप हरिजन नेताओं ने उनके खिलाफ बयान जारी किये। प्रान्तीय अखबारों में सम्पादकीय लिखकर उनके सोच की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान हरिजन सेवक संघ का उद्घाटन करते हुए सी०पी० जोशी के रवैये पर कटाक्ष किया था। सारे प्रकरण में हरिजन विरोधी के रूप में कांग्रेस-इ विधायक सी०पी० जोशी नजर आते हैं। 'माया' ने सी०पी० जोशी से इस मामले में विस्तार से बातें की हैं। प्रस्तुत हैं, साक्षात्कार के कुछ अंश :

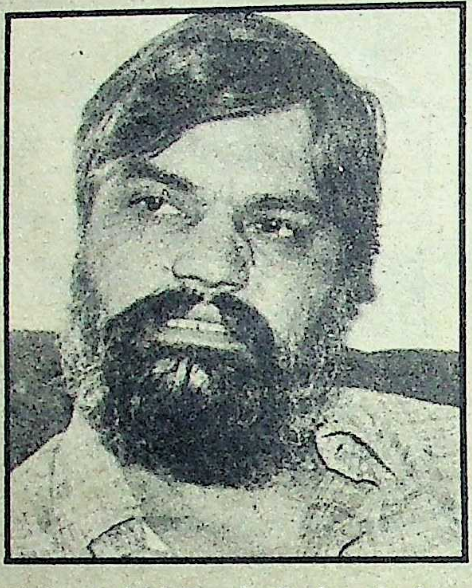

माया : क्या यह सच है कि मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में संकट में डाल दिया ?

जोशी : नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता। बहरहाल, यह जरूर महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्रीजी का जो 'वे ऑफ वर्किंग' (काम करने का तरीका) है, उसमें वे अपने अनुभव से समस्या का निदान सोचते हैं, पर मैं अपने दृष्टिकोण से सोचता हूं। लोकतंत्र में ज्यादा-से-ज्यादा लोगों से मिलकर अगर समस्या का समाधान किया जाये, तो वह ठीक होता है। वे हर समस्या को अपने स्तर पर सुलझाते हैं, इससे जरूर ऐसा लग सकता है। वैसे अखबारों में मेरे लिए मुख्यमंत्री के नाम से जो भी कुछ छपा है, उन्होंने उसका खंडन किया है।

माया : क्या श्रीनाथजी के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश वर्जित है ?

जोशी : मैं बहुत लम्बे समय से नाथद्वारा से जुड़ा हूं। मैंने स्वयं देखा है कि श्रीमती जगजीवन राम, श्रीमती पहाड़िया, दिनेश राय डांगी, मांगीलाल आर्य जैसे व्यक्ति बराबर जाते रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वहां प्रवेश वर्जित है।

माया : फिर समारोहपूर्वक हरिजन प्रवेश का प्रचार क्यों हुआ ?

जोशी : मैं खुद इससे आश्चर्यचकित हूं। कारण यह है कि मैं दो बार इस विधान सभा क्षेत्र को रिप्रजेन्ट (प्रतिनिधित्व) कर चुका हूं। इस सारे घटनाक्रम में मुझसे हरिजन सेवक संघ के किसी भी आदमी ने सम्बन्ध स्थापित नहीं किया, न ही सरकार के किसी प्रतिनिधि ने कुछ बताया। मंदिर मण्डल के किसी व्यक्ति ने भी यह नहीं बताया कि क्या कुछ होने जा रहा है। मुझे तो मुख्यमंत्री के पी०ए० ने उनके प्रोग्राम के एक दिन पहले यह बताया कि उनका क्या प्रोग्राम है। आइ वाज शाक्ड। बारह जून को मुख्यमंत्री किसी विवाह के सिलसिले में काकरोली आये, जहां से हम उनके साथ उदयपुर गये थे, वहां कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। इतने बड़े घटनाक्रम में मेरी भी कोई भूमिका हो सकती है, यह मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। वह उदयपुर सम्भाग से वाकिफ हैं। वहां की संवेदनशीलता को जानते हैं, नाथद्वारा के बारे में जानते हैं, फिर क्यों वहां के प्रतिनिधि (सी०पी० जोशी) को अनभिज्ञ रखा गया ?

माया : मुख्यमंत्री से आपने प्रचार बंद करने के सम्बन्ध में कहा था ?

जोशी : मैंने सारी घटनाओं के सम्बन्ध में जानना चाहा, तब उन्होंने बताया कि हरिजन सेवक संघ से मेरा पुराना सम्बन्ध है। हरिजन सेवक संघ ने अखिल भारतीय स्तर पर मंदिर में प्रवेश का निर्णय लिया है और निर्णय के बाद महाराजश्री (तिलकायतजी) से सम्बन्ध स्थापित किया है। उनकी राय के मुताबिक ही ऐसा (मंदिर प्रवेश) हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि महाराजश्री को यह बात जनता (नाथद्वारा की) को बता देनी चाहिए थी। फिर मेरी तो महाराजश्री से कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल, मैंने मुख्यमंत्री को सारी स्थितियों से अवगत करा दिया था।

माया : आप कहते हैं, नाथद्वारा में हरिजन-विरोधी माहौल नहीं है, तो नाथद्वारा दो दिन क्यों बंद रहा ?

जोशी : यह बड़ा स्वाभाविक असर था। अगर कोई व्यक्ति अजमेर की दरगाह में जियारत करने जाता है या चर्च में जाता है, तो वहां की परम्पराओं का पालन करता है। ऐसे में आप परम्परा तोड़ने की बात करेंगे, तो लोग नाराज होंगे ही।

माया : क्या प्रवेश करनेवालों ने कण्ठी-डोरा धारण करने से इनकार किया था ?

जोशी : नहीं, मुझे बताया गया कि वे कण्ठी-डोरा धारण करके ही जानेवाले थे। पर जब लम्बे अरसे से हरिजन श्रीनाथजी के मंदिर में दर्शन करते रहे हैं, तो प्रवेश-प्रचार से लोगों की आस्था को आहत करने का क्या अर्थ ? नाथद्वारा के लोगों की रोजी-रोटी का एकमात्र आधार श्रीनाथजी का मंदिर है। मंदिर में हरिजनों के सामूहिक रूप से प्रवेश का प्रचार वैष्णव जनों की दृष्टि में मंदिर की मर्यादा पर असर डालता। उनके श्रीनाथजी के मंदिर से किनारा करने पर आर्थिक रूप से समूचा नाथ द्वारा प्रभावित होता है। वैसे नाथद्वारा में रिलिजियस हारमनी (धार्मिक सद्भावना) है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां आज भी मंदिर मण्डल का लेखाधिकारी एक आदिवासी है। मंदिर मण्डल के प्रशासक का सचिव एक क्रिश्चियन धर्म का माननेवाला है। सब्जियां और फल मंदिर को मुस्लिम वर्ग के लोग सप्लाई करते हैं। इस हारमनी (सद्भावना) को क्यों डिस्टर्ब किया जाये। वैसे इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि महाराजश्री इसकी जनता के बीच घोषणा करते।

माया : इस घटना से प्रदेश में सवर्णों और हरिजनों का विवाद नहीं बढ़ेगा ?

जोशी : मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा।

माया : आपका मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुखर रहना ही क्या सारे विवाद की जड़ है ?

जोशी : मैं इसे इस दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन यह समझ रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले भाजपा और जनसंघ का वर्चस्व रहा है। हमने धीरे-धीरे यह वर्चस्व समाप्त किया है। पर पिछले छह माह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो। वैसे, नाथद्वारा राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है। वहां, विभिन्न दलों के पांच पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद सक्रिय हैं। उन्हें लगता है कि मुझ जैसा नौजवान दो बार विधायक बन गया, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। मेरी राजनीति में प्रतिबद्धता बड़ी स्पष्ट है। मैंने पहले अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को माना था और अब श्री राजीव गांधी को मानता हूं। अपने दल और विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात मैं जरूर कहूंगा, इससे कोई नाराज होता है, तो हो जाये।

माया : आपको नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस की पराजय के बाद आलाकमान पुराने नेताओं को ज्यादा तरजीह देने लगा है ?

जोशी : देखिये, अभी तक कांग्रेस के लोग तीस प्रतिशत की राजनीति करते थे। तीस प्रतिशत का मतलब यह है कि सवा लाख की आबादीवाले एक विधान सभा क्षेत्र में बीस या पच्चीस हजार मत प्राप्त करनेवाला उनका प्रतिनिधि बन जाता था। पर अब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और कांग्रेस के उम्मीदवार को अपनी विजय के लिए पचास प्रतिशत मत हासिल करने होते हैं। १९५२ से राजनीति करनेवाले हमारे बड़े नेताओं ने तीस प्रतिशत मतों से प्रतिनिधित्व हासिल किया है। ऐसे लोग हरियाणा के चुनाव परिणामों से परेशान हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी पकड़ हवा में नहीं जमीन पर है। इसलिए पुरानों के गाल बजाने से कुछ नहीं होनेवाला।

भेंटकर्ता : ओम सैनी

गगनचुंबी इमारतों में सुलगता खतरा

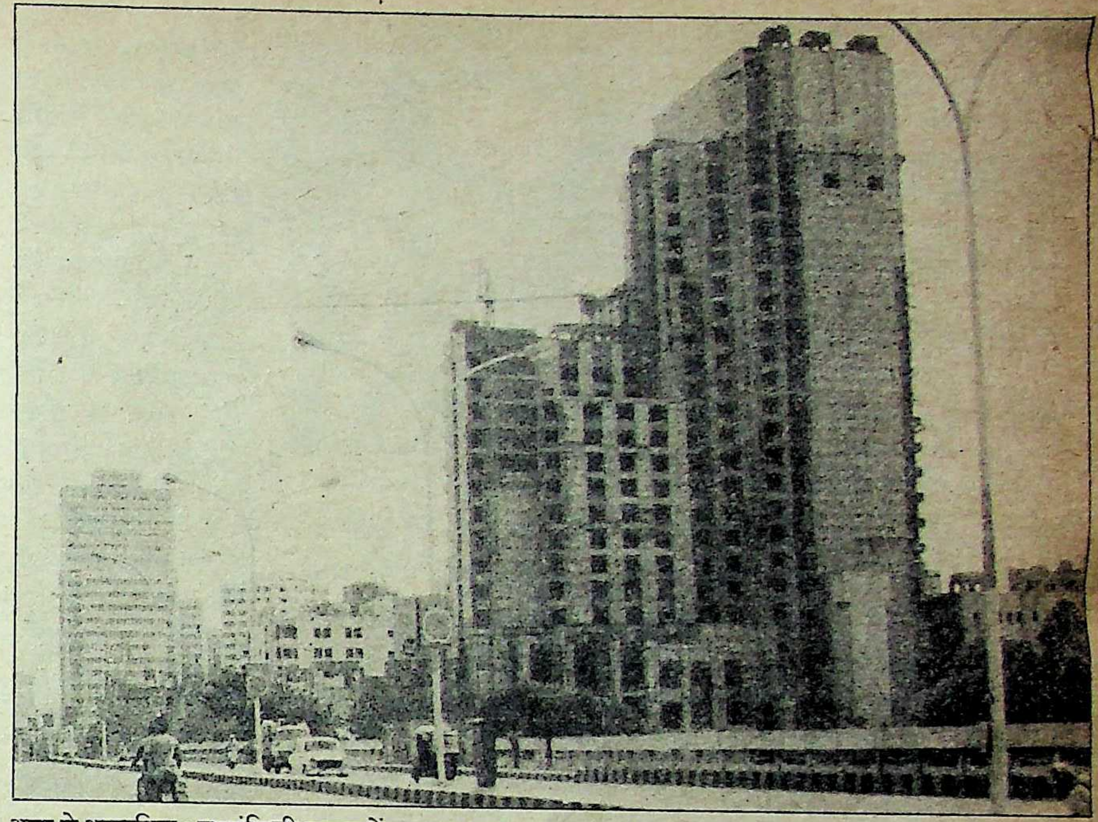

आग से असुरक्षित : बहुमंजिली इमारतों का एक दृश्य

दिल्ली की अस्सी प्रतिशत ऊंची इमारतें ऐसी हैं, जिनमें आग लगने की पूरी आशंका होते हुए भी बचाव के प्रबंध पूरे नहीं हैं। दूसरी ओर, दिल्ली की ८० लाख की आबादी को देखते हुए, यहां कम-से-कम ६३ दमकल केंद्र होने चाहिए, लेकिन हैं, सिर्फ १९। सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि दिल्ली की खतरनाक घोषित १९४ इमारतों में से १०७ इमारतें सरकारी हैं। आग लगने पर इन इमारतों में फंसे लोगों को कौन बचायेगा ? क्या दिल्ली के सत्ताधारियों ने आग के मामले में दिल्ली को भगवान-भरोसे छोड़ दिया है ?

दिल्ली में सरकार आग से खेल रही है। राजधानी की करीब ३५० बहुमंजिली (१५ मीटर से ऊंची) इमारतों में से १९४ में आग से बचने के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। इन १९४ खतरनाक इमारतों में से १०७ इमारतें सरकारी हैं। सरकार खुद अपने कानून को खुलेआम तोड़ रही है। दूसरी ओर दिल्ली में दमकल सेवा सिसक रही है। जब भी दिल्ली में आग लगने की कोई बड़ी वारदात होती है, सरकार सकते में आकर कुछ करती है और फिर जैसे सो जाती है। ६ जून १९८३ को १४ मंजिले गोपाल टावर में आग लगने पर सरकार ने २३ जून, १९८३ को एकीकृत भवन कानून बनाया। २३ जनवरी, १९८६ को सिद्धार्थ कांटीनेंटल में आग लगी, जिसमें २२ विदेशियों (दो राजनयिक) सहित ३८ लोग मरे थे, तब सरकार ने अगस्त, १९८६ में दिल्ली अग्नि निरोधक और अग्निसुरक्षा क़ानून, १९८६ संसद से पास कराया। फिर सरकार सो गयी। इस कानून को १२ दिसंबर, १९८६ को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। इसके नियम मार्च, १९८६ में बने और अप्रैल, १९८७ में यह कानून लागू हो पाया। अब २९ जून को ११ मंजिले अंसल भवन में लगी आग पर सरकार फिर सकते में है। इस बार वह क्या करती है, यह देखना है।

राजधानी में आग लगने से मरनेवालों की संख्या १९८५-८६ में ३१६ और ८६-८७ में २५५ थी। १९७८-७९ में आग आदि के ३६३८ मामले दिल्ली दमकल सेवा में दर्ज हुए थे, जो १९८६-८७ में ६७५१ थे। आग से होनेवाली क्षति भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। १९७८-७९ में एक करोड़, २९ लाख का नुकसान हुआ था जो १९८६-८७ में बढ़कर छह करोड़, ५८ लाख रुपए का हो गया। इसके पहले विस्तार के लिए १९६५ में ७३.४४ लाख और १९६९ में ९.६ लाख रुपए दिये गये थे।

अक्षम दमकल विभाग : दिल्ली की अनेक इमारतें आग पर बैठीं हैं, दूसरी ओर सरकार दमकल की जरूरतों के बारे में चुप्पी साधकर बैठी है। १९७६ में विशेषज्ञों की समिति ने दिल्ली में ६३ दमकल केन्द्रों को १० साल में बनाने की सिफारिश की थी। पर १९७६ में १३ दमकल केन्द्र थे, अब १९ हैं। दिल्ली दमकल के आधुनिकीकरण के लिए ५० करोड़ से भी ज्यादा धन की जरूरत है, पर केन्द्र सरकार ने पिछले साल ५ करोड़ और चालू साल में ६.८३ करोड़ रुपए दिये हैं। दिल्ली दमकल को ६ हजार कर्मचारियों की जरूरत है, पर कर्मचारियों की मौजूदा संख्या महज एक हजार है। १९४२ में दिल्ली दमकल का गठन हुआ था। उस साल पांच लाख की आबादी पर पांच दमकल केन्द्र और १८६ कर्मचारी थे। १ जुलाई, १९८६ को दिल्ली की आबादी ८० लाख से ज्यादा हो गयी है, पर १० दमकल केन्द्र और १००० कर्मचारी हैं। जहां इस काम के लिए फुर्तीले और जवान कर्मचारी चाहिए, वहीं दिल्ली दमकल सेवा के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र ५३ साल से बढ़ाकर ६० साल कर दी गयी है।

कंक्रीट का जंगल बनती जा रही राजधानी की ऊंची इमारतों में आग लगना नयी बात नहीं है। हर बार आग के बाद जांच का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ आग ठंडी पड़ती है, दूसरी ओर आग की जांच-रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पहुंच जाती है। इस बार अंसल भवन में लगी आग की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डी०एम० सपोलिया कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का भी यही हश्र हो तो ताज्जुब नहीं।

दिल्ली में इमारतों के नक्शों को मंजूरी देते समय न तो उनमें आग बुझाने के आंतरिक उपकरणों और सुविधाओं का ध्यान रखा गया, न ही दिल्ली दमकल की क्षमता का। दिल्ली दमकल के पास सीधे ४४ मीटर ऊपर तक लगी आग बुझाने के साधन हैं, जबकि दर्जन भर इमारतें ६० मीटर और उससे ऊंची हैं। हजारों दुकानों-दफ्तरोंवाले नेहरू प्लेस को इस तरह बनाया गया है, जिसमें गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती। यहां कारोबार के समय एक लाख से भी ज्यादा लोग होते हैं। ऐसे में अगर आग

साक्षात्कार/एस०के० ढेरी

दिल्ली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी

साधन लगे हों, तो फिर ऊंचाई कोई समस्या नहीं है

दिल्ली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी एस०के० ढेरी को आग से खेलते हुए करीब तीन दशक हो गये, पर उन्होंने अपनी छवि पर कभी आंच नहीं आने दी। दिल्ली दमकल में नौकरी का यह उनका दूसरा दौर है। १९५८ में दिल्ली दमकल की अफसरी छोड़कर वे हिमाचल प्रदेश चले गये। वहां २५ साल तक मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रूप में ज्यादातर जंगलों की आग से जूझते रहे। १९८३ से वह दिल्ली में मौजूदा पद पर हैं। दिल्ली अग्नि निरोधक और अग्निसुरक्षा कानून, १९८६ बनने-बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। २९ जून को अंसल भवन में लगी आग का सामना उनके तहत जिस तरह दिल्ली दमकल ने किया, उसकी प्रशंसा चारों ओर हुई। उन्हें प्रशंसा से भरे पत्र प्राप्त हो रहे हैं। पत्र लिखनेवालों में बंबई और कलकत्ता दमकल के अधिकारी भी हैं। ११ जुलाई को छुट्टी के दिन भी वे दफ्तर में जमे थे। वहीं पर 'माया' से उनकी खुली बातचीत हुई।

माया : दिल्ली में कितनी इमारतें अरक्षित हैं ? यह खामी कब तक दूर होगी ?

ढेरी : १९४ बहुमंजिली इमारतें अरक्षित हैं। इन्हें निरापद बनाने में समय लगेगा। जब तक इमारतों के भीतर अग्निशमन यंत्र नहीं लगाये जाते, अरक्षा रहेगी। कुछ भवनों में केवल एक ही सीढ़ी का प्रावधान है, जबकि आग से बचने के लिए अलग सीढ़ी बाहर की तरफ होनी चाहिए, ताकि उसमें धुआं नहीं भरे, लोग आराम से बाहर निकल कर आ सकें।

माया : इनमें से कितनी सरकारी हैं ?' उन्हें निरापद बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

ढेरी : इनमें से १०७ सरकारी हैं। जिस तरह हम निजी इमारतों को नोटिस देते हैं, उसी तरह सरकारी इमारतों को भी। उन्हें भी उसी तरह दंडित किया जायेगा। यदि सजा देने पर भी खामियां दूर नहीं होतीं, तो हम उन्हें निरापद बनाकर खर्च भूमि राजस्व की तरह उनसे वसूल करेंगे।

माया : एक इमारत में आग बुझाने के उपकरणों की क्या लागत आती है ?

ढेरी : आजकल बिल्डर्स २५-३० रुपए प्रति वर्गफुट के हिसाब से मांग रहे हैं। पर नयी इमारत में खर्च कम आयेगा। जो भी इमारत ४५ मीटर से ऊपर है, उसमें सौ फीसदी स्प्रींकलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसमें आग की सूचना भी अपने आप मिल जायेगी और आग भी अपने आप बुझनी शुरू हो जायेगी। करीब २५-३० लाख रुपए खर्च बैठेगा।

माया : आप कितने मंजिल तक की आग बुझाने में सक्षम हैं ?

ढेरी : सक्षमता हमारी इमारतों के अंदर लगे साधनों पर निर्भर करती है। दुनिया में १२० मंजिल तक की इमारतें बन रही हैं। पर अभी तक सबसे ऊंची सीढ़ी ६१.५ मीटर की ही बनी है। इसलिए जब तक इमारत के अंदर अग्निशमन यंत्र नहीं लगे हों, बाहर से आग बुझाना मुश्किल है। साधन लगे हों, तो फिर ऊंचाई कोई समस्या नहीं है।

माया : आपने साधनों की कमी की चर्चा की। क्या कमी है ?

ढेरी : १९७६ में विशेष समिति ने ६३ दमकल स्टेशनों की सिफारिश की थी तब दमकल स्टेशन १३ थे अब १९ हैं, और सात निर्माणाधीन हैं। सरकार इस बारे में कोशिश कर रही है। मैंने इस बारे में अपनी जरूरतें बता दी हैं। हर साल ५-७ स्टेशन बनेंगे, तो कुछ वर्षों में हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे।

माया : अभी आपको अधिकतम दूरी कितनी तय करनी होती है ?

ढेरी : महरौली में आग लगने पर सफदरजंग से और नेहरू प्लेस, ओखला, कालकाजी आदि में आग लगने पर आश्रम से दमकल भेजी जाती हैं। कहीं-कहीं १५ किलोमीटर की दूरी भी तय करनी होती है। दूरी के साथ इलाका भी मायने रखता है। कुछ स्थान जैसे चारदीवारी की दिल्ली में भीड़भाड़ के कारण पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है।

माया : पर १५ किलोमीटर पहुंचने में जितना वक्त लगेगा उतने में तो छोटी-सी आग भी भयानक विनाश कर देगी।

ढेरी : इसीलिए हम सरकार को ६३ दमकल केन्द्रों के लिए कह रहे हैं।

माया : एक दमकल केन्द्र बनाने में कितना वक्त लगता है ?

ढेरी : इंजीनियरिंग महकमे के पास पूरे साधन हों तो एक साल।

माया : इस रफ्तार से कितने सालों में अपनी जरूरतों को पूरा कर पायेंगे।

ढेरी : जो योजना मैंने भेजी है, उस पर अमल हुआ तो चार साल में। अभी जितना स्टाफ होना चाहिए उसका छठा हिस्सा ही है।

माया : जब भी आग लगती है, दिल्ली दमकल पर देर से पहुंचने का आरोप लगता है ?

ढेरी : मैंने अपनी २८ साल की नौकरी में कभी नहीं सुना कि दमकल फोन करते ही पहुंच गयी। जिसके घर-जायदाद में आग लगी होती है, जो लोग वहां देख रहे होते हैं, उनके लिए एक-एक सेकेंड एक-एक घंटे के बराबर लगता है। हो सकता है, जब मेरे घर में आग लगे, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हो। ट्रैफिक जाम, रवाना, होना, रास्ता तय करना—इसमें आखिर कुछ तो समय लगता ही है। मैं नहीं मानता कि देरी होती है। काल मिलने के ६० से ९० सैकेंड में हम रवाना हो जाते हैं।

माया : दिल्ली अग्नि निरोधक और अग्नि सुरक्षा कानून के तहत कितने दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए ?

ढेरी : यह हमारे ऊपर है जो इमारत की जरूरत को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

माया : आपने अंसल भवन में आग लगने के बाद ही सभी १९४ इमारतों को नोटिस क्यों दिये ? पहले भी तो दिये जा सकते थे ?

ढेरी : कानून पहली अप्रैल से अमल में आया। नामजद अधिकारी को एक-एक इमारत का पुख्ता मुआयना कर नोटिस में बताना होता है कि यह-यह खामियां हैं। यह काम हमने एक दिन में ही नहीं कर लिया। काम चल रहा था। यह अलग बात है कि आग लगने के बाद अतिरिक्त स्टाफ को लगाकर काम पूरा किया गया।

माया : आपने अप्रैल से सर्वे शुरू किया, पर नोटिस ३० जून को ही सबको दी। जितनी इमारतों के सर्वे हो चुके थे, उतने को तो नोटिस पहले दिया ही जा सकता था।

ढेरी : स्टाफ की कमी है। तीन अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। नये कानून के अमल में वक्त तो लगता ही है। हमने स्टाफ मांगा है। स्टाफ मिलने पर काम जल्दी होगा।

माया : गोपाल टावर में आग लगने पर एकीकृत भवन कानून बना। सिद्धार्थ कांटीनेंटल में आग लगने पर नया कानून बना। जब हर बड़ी आग के बाद आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो इस बार अंसल भवन की आग के बाद आपका क्या कदम होगा ?

ढेरी : (हंसते हुए) अगर दमकल सेवा का विस्तार शुरू से होता, अगर भवन-कानून सही समय पर बन जाते, तो ये कायदे-कानून बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्हें बनाने में ही १० साल से ऊपर समय लगा, अगर आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध हों, लोगों को ठीक से समझाया जाये, इमारतों की लगातार जांच होती रहे, तकनीकी अभ्यास कराया जाये, देखा जाये कि पांच-सात मिनट में पूरी इमारत खाली होती है या नहीं, तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। हमने यूरोप से ऊंची इमारतों की संस्कृति की नकल तो कर ली, लेकिन इनमें रहनेवालों की संस्कृति अभी तक हमारे यहां नहीं पहुंची।

(इसी समय वहां संसद की एनेक्सी में आग लगने की खबर आती है और बातचीत समाप्त हो जाती है।)

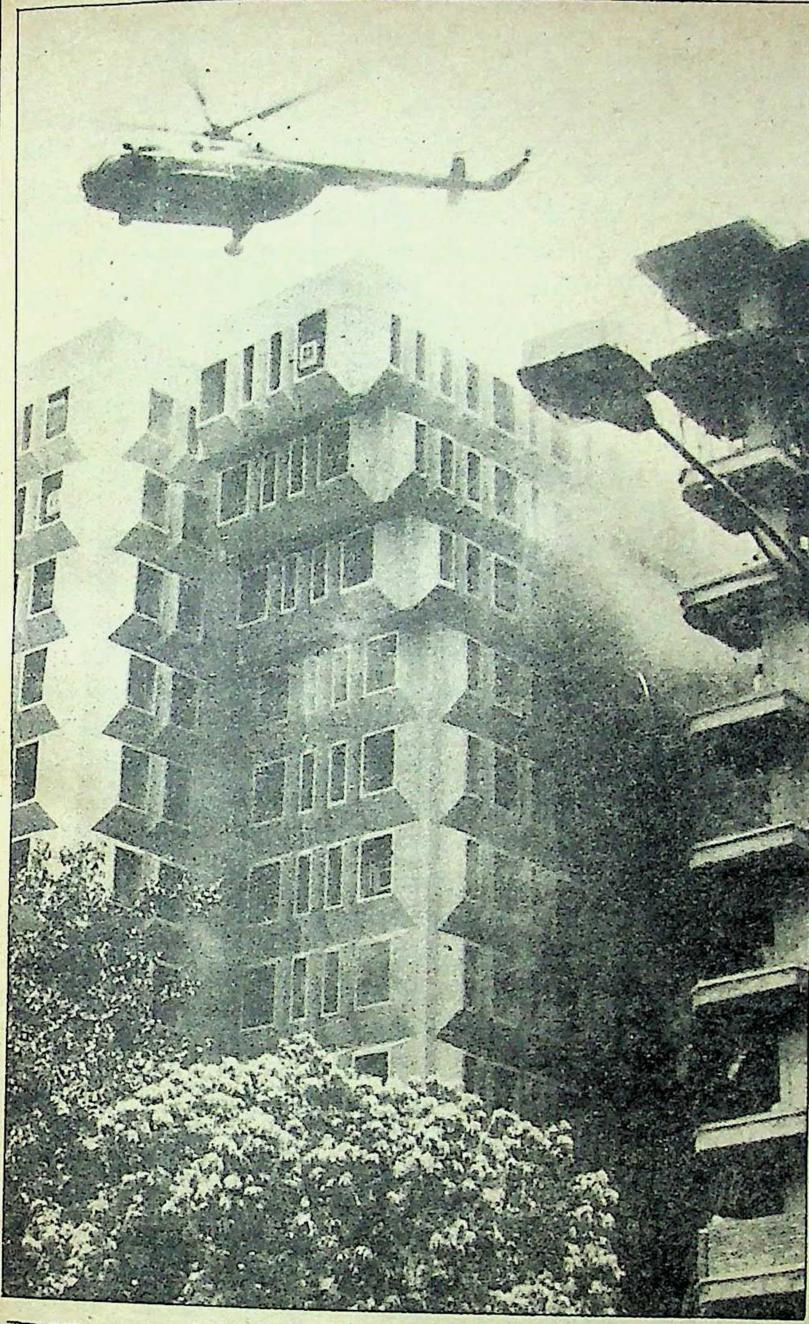

क्या सरकार सबक लेगी ? : अंसल भवन में लगी आग

दिल्ली के अग्निकांड

वर्ष	दिल्ली दमकल में दर्ज आग के मामलों की संख्या	नुकसान लाख रुपए में
१९७८-७९	३६३८	१२९.२४
७९-८०	३९५१	१९४.६९
८०-८१	४१९९	१९२.७९
८१-८२	४४८६	२८८.७७
८२-८३	५०९६	४३७.१०
८३-८४	५५२४	३४६.७५
८४-८५	६७२५	१३५८.१६
८५-८६	६५१८	४६१.५३
८६-८७	६७५१	६५७.६१

(सौजन्य : दिल्ली दमकल सेवा)

लग जाये, तो दमकल कैसे पहुंचेगी ? इन एक लाख लोगों का क्या होगा ? इसी तरह खतरे वाली १०७ सरकारी इमारतों में से ९ अस्पताल और ७ बड़े होटल भी हैं। इनके अलावा सरकारी कर्मचारियों के फ्लैट और दफ्तर हैं। इनमें लाखों लोगों की जान कैद है।

लापरवाही की मिसालें : इसके बावजूद भयंकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके दर्जनों उदाहरण हैं। सिद्धार्थ कांटीनेंटल में लगी आग की जांच दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज डी०आर० खन्ना ने की थी। उनकी जांच रिपोर्ट ६ महीने तक धूल चाटती रही। जब अंसल भवन में आग लगी तब जाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के पांच अफसरों को मुअत्तल किया गया। इन अफसरों ने सिद्धार्थ कांटीनेंटल का नक्शा पास करने में नियमों को ताक पर रख दिया था। खास बात यह है कि आज तक इस रिपोर्ट को गोपनीय दस्तावेज बनाकर प्रशासन लीपापोती में लगा है।

लापरवाही की एक-से बढ़कर-एक मिसालें हैं। १९७१ में ही तत्कालीन आवास-मंत्री इन्द्रकुमार गुजराल ने कहा था कि इमारतों के नक्शे पास करने में दमकल की मंजूरी ली जानी चाहिए। २१ जुलाई, १९८३ को दिल्ली महानगर परिखद ने दिल्ली अग्निसेवा विधेयक, १९८३ पास किया। इस विधेयक में दमकल सेवा दिल्ली नगर निगम से लेकर दिल्ली प्रशासन को सौंपने का प्रावधान था। इसके पहले १९४२ से १९५८ तक दमकल सेवा दिल्ली प्रशासन के तहत ही थी, लेकिन आज तक भी दमकल सेवा नगर निगम के पास है। ९ जुलाई १९८७ को महानगर परिषद में अंसल भवन में लगी आग की चर्चा के दौरान यह मांग दोहराई गयी, जबकि गृहमंत्रालय के निर्देश के अनुसार अग्निशमन सेवा सीधे राज्य सरकार के जिम्मे होनी चाहिए। इस दृष्टि से दिल्ली में यह सेवा दिल्ली प्रशासन के अधीन होनी चाहिए।

संसद में सांसद रशीद मसूद के सवाल पर १२ सितंबर, १९८३ को तत्कालीन निर्माण और आवास उपमंत्री मोहम्मद उस्मान आरिफ ने बताया था कि दिल्ली में ८० फीसदी ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। आज भी दिल्ली की १९४ इमारतें ऐसी ही श्रेणी में आती हैं। तब इनकी संख्या करीब ३३० थी। जाहिर है कि सरकार और दिल्ली प्रशासन से मेलजोल के कारण ही ये ऊंची इमारतोंवाले बचे हुए हैं। इसकी मिसाल है 'द फेडरेशन आफ होटल ऐंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन' के अध्यक्ष रामप्रसाद का ३१ जनवरी, १९८५ को दिया गया बयान। रामप्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सभी होटलों में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम हैं। दूसरी ओर अगले ही महीने आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण कई होटलों को पानी और बिजली के कनेक्शन काटने के नोटिस दिये गये। पूर्व इंकासांसद चरणजीत सिंह के पांचतारा होटल 'मेरीडियन' की बिजली पहली जनवरी, १९८६ को काट दी गयी थी। पर खुद उपराज्यपाल हरिकिशन लाल कपूर ने इसकी बिजली जुड़वा दी। जहां तक होटल मालिकों का रवैया है, वह आमदनी की चिंता करते हैं, आग से लोगों को होने वाले नुकसान की नहीं। तत्कालीन पर्यटन मंत्री हरिकिशन लाल भगत ने २५ फरवरी, १९८६ को बताया था कि होटल सिद्धार्थ ने आग लगने के १५ दिन पहले ही दिल्ली दमकल सेवा और दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिग महकमे को लिखकर दिया था कि उसके आग बुझाने वाले उपकरण पुख्ता हाल में हैं।और-तो-और सरकारी होटल—अशोक में आज तक अग्निशमन उपकरण नियमानुसार नहीं हैं।

चौदह मंजिले गोपाल टावर में ६ जून, १९८३ को लगी आग के बाद दिल्ली प्रशासन ने मेजर जनरल एच०एन० सिंघल की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति बनायी थी। समिति ने करीब ३३० बहुमंजिली इमारतों की बनावट और आग बुझानेवाले उपकरण त्रुटिपूर्ण पाये थे। इस कमेटी ने ऊंची इमारतों के लिए स्वचालित छिड़काव यंत्र की सिफारिश की थी। तब यंत्र की कीमत ३० लाख रुपए थी। आज तक इनमें से कुल २६ ने एहतियाती इंतजाम किये हैं।

इसी तरह १० फरवरी, १९८५ को शक्तिनगर में शामियाने में आग लगने के कारण ८ लोगों की मौत हो गयी थी। दिल्ली दमकल सेवा ने तब २१ एहतियाती उपाय बताये थे, पर किसी ने परवाह नहीं की। नतीजतन, २६ फरवरी, १९८६ को अशोक विहार में जन्मदिन की पार्टी के दौरान शामियाने में आग लगने से फिर ७ लोग मरे और ९४ जख्मी हुए। तब जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नलिनी जैशीलन ने की। इस रिपोर्ट का क्या हुआ, किसी को पता नहीं। और तो और, १९७६ में मिली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बहुत से हिस्सों पर आज तक अमल नहीं हुआ। ऐसे में अंसल भवन में लगी आग की जांच करके बलि के लिए कुछ चेहरे तो तय किये ही जा सकते हैं, पर समस्या का समाधान नामुमकिन ही लगता है।

कागजी कानून : दिल्ली अग्नि-निरोधक और अग्नि-सुरक्षा कानून के संसद में पास होने से लेकर अमल में आने तक आठ महीने लगे। इस ढील के पीछे भी लापरवाही ही है। खास बात यह है कि इस कानून के प्रावधानों को असल भवन में आग लगने तक आजमाया भी नहीं गया। सभी १६४ खतरनाक इमारतों को नोटिस हादसे के अगले दिन, यानी ३० जून को अफरातफरी में दिये गये। जबकि इस कानून के प्रावधान बहुत सख्त हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी किसी इमारत को अग्नि-रक्षा के उपाय पूरे करने के लिए उचित नोटिस देगा। अमल नहीं होने पर इमारत सील की जा सकती है। छह महीने जेल या ५० हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। फिर भी नहीं मानने पर तीन हजार रुपए रोज तक जुर्माना किया जा सकता है। इन निरंकुश अधिकारों पर अदालती अंकुश भी नहीं है। मुख्य-अग्निशमन अधिकारी के फैसले की अपील पहले नगर निगम के अतिक्रमण से निबटनेवाले मजिस्ट्रेट और फिर उपराज्यपाल ही सुन सकते हैं। लेकिन इन कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है।

जिस समय गोपाल टावर में आग लगी, उस समय दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अपने-अपने भवन कानून थे। इनमें से डीडीए और छावनी बोर्ड के भवन कानून अग्निसुरक्षा की दृष्टि से नाकाफी थे। दरअसल, एकीकृत भवन कानून का आधार १६७० में ही तैयार हो गया था। ये १३ साल तो दिल्ली प्रशासन ने लापरवाही में गंवाये। जब गोपाल टावर में आग लगी, तो उन्हें इसकी याद आयी। भारतीय मानक संस्थान ने भारत सरकार के कहने पर १६७० में राष्ट्रीय भवन संहिता बनायी थी। इसे बनाते समय राज्य सरकारों, भवन निर्माताओं, वास्तुकारों, इंजीनियरों तथा दमकल अधिकारियों की राय और विदेशों में अग्निसुरक्षा के तौर-तरीकों को ध्यान में रखा गया था। भारत सरकार ने इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा था।

दिल्ली के विषय में सरकार ने इस संहिता के तहत भवन निर्माण कानून बनाने के लिए भारतीय मानक संस्थान के तहत कमेटी बनायी थी। इस कमेटी में छावनी बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम और डीडीए को भी रखा गया। इस कमेटी ने १६७६ में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ६ जून, १६८३ को गोपाल टावर में आग लगी और २३ जून को 'एकीकृत भवन कानून' उसी रिपोर्ट के मद्देनजर बनाया गया। सिद्धार्थ होटल अग्निकांड की जांच रिपोर्ट के अनुसार, "मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इन कानूनों के तहत निरीक्षण, निर्देशन और अमल में स्थानीय निकायों और दिल्ली अग्निशमन सेवा की कुछ दिक्कतें महसूस की गयीं। इन कानूनों के वास्तविक अमल के लिए तब अग्नि-सलाहकार समिति ने कुछ और कानून बनाने की राय दी। ये प्रस्तावित कानून फिर लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर रह गये और इन्हें अब भी विधायी ताकत बनना है।"

सुरक्षा उपायों की उपेक्षा : उच्चन्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डी०आर० खन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट में, डीडीए की लापरवाहियों पर भी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, "तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल, जिनके नाम मेजर जनरल एच०एन०सिंघल (अवकाश प्राप्त), नागरिक सुरक्षा, भारत सरकार के पूर्व महानिदेशक और गृहमंत्रालय, भारत सरकार के अग्नि सलाहकार (पूर्व) पी०एन० मेहरोत्रा तथा गृहमंत्रालय, भारत सरकार के उपअग्निसलाहकार एस०के० मुखर्जी ने मुझे ध्यान दिलाया कि दिल्ली की ज्यादातर मौजूदा ऊंची इमारतें 'टावरिंग इनफरनोज' (एक विदेशी फिल्म का नाम, जिसमें एक ऊंची इमारत में आग लगने से हुई भयावह स्थिति का सटीक चित्रण था) साबित हो सकती हैं। और अगर व्यस्तता के समय, जबकि इमारत लोगों से ठसी रहती है, आग लग जाये, तो जानमाल की भारी क्षति हो सकती है। यह जांच आयोग २१ मंजिले विकास मीनार भवन की जांच कर रहा है। यहां एक ही सीढ़ी है और वह भी लिफ्ट की ओर। आग लगने पर इस्तेमाल होनेवाली दूसरी सीढ़ी भी इसी से सटी है।...यह कैसी विडंबना है कि महानगर के विकास में अग्रणी भूमिका के निर्वाह के लिये जिस दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, उसने अपनी ही इमारतों की योजना में अग्नि-सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की है।"

न्यायमूर्ति खन्ना ने आग से हिफाजत के लिए अपनी १६३ पेजी रिपोर्ट में २८ सुझाव दिये हैं। इसी तरह अग्निशमन सेवा को दुरुस्त बनाने के लिए भी २१ सुझाव दिये हैं। महीनों बाद भी इन सुझावों पर अमल के आसार अस्पष्ट हैं।

असली समस्या एकीकृत भवन कानून के अमल में आने से पहले बनी इमारतों

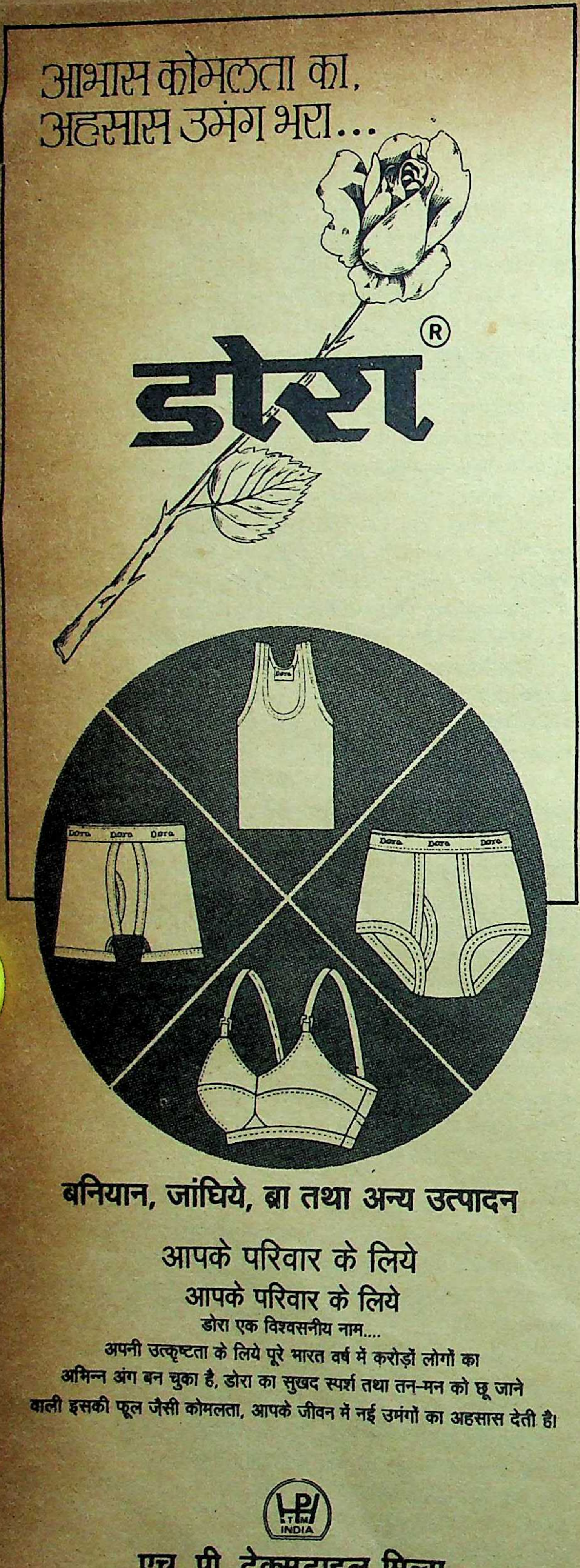

आभास कोमलता का,
अहसास उमंग भरा...

डोरा®

बनियान, जांघिये, ब्रा तथा अन्य उत्पादन

आपके परिवार के लिये
आपके परिवार के लिये
डोरा एक विश्वसनीय नाम....
अपनी उत्कृष्टता के लिये पूरे भारत वर्ष में करोड़ों लोगों का
अभिन्न अंग बन चुका है, डोरा का सुखद स्पर्श तथा तन-मन को छू जाने
वाली इसकी फूल जैसी कोमलता, आपके जीवन में नई उमंगों का अहसास देती है।

HP
INDIA

एच. पी. टेक्सटाइल मिल्स
कलकत्ता - अहमदाबाद - नई दिल्ली

मौत के मुंह में बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी

अंसल भवन में आग लगने के बाद यह पाया गया कि दिल्ली की १६४ इमारतें ऐसी हैं, जिनमें यदि आग लग जाये, तो वहां फंसे लोगों का बच पाना संदिग्ध है और इनमें १०७ इमारतें सरकारी हैं।

इन इमारतों के नाम हैं—गफ्फार मार्केट (करोल बाग), ईदगाह टेलीफोन एक्सचेंज (फैज रोड), वरुणालय (झंडेवाला), तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, हिंदूराव अस्पताल (तीन इमारतें), जीवन प्रकाश (कस्तूरबा मार्ग), जीवन दीप (संसद मार्ग), जीवन विहार (संसद मार्ग), जीवन तारा (संसद मार्ग), बैंक आफ बड़ोदा (संसद मार्ग), इलाहाबाद बैंक (संसद मार्ग), उद्योग भवन (जनपथ), राष्ट्रीय संग्रहालय (बीके रोड), मयूर भवन (कनाट प्लेस), चंद्रलोक बिल्डिंग (जनपथ), बड़ोदा हाउस (कस्तूरबा मार्ग), विदेश मंत्रालय (कस्तूरबा मार्ग), एशिया हाउस (कस्तूरबा मार्ग), होटल जनपथ, अशोक यात्री निवास, सरदार पटेल भवन (अशोक रोड), किदवई भवन (जनपथ रोड), सुपर बाजार (कनाट प्लेस), मोहन सिंह प्लेस (बाबा खड़क सिंह मार्ग), सिटी सेंटर (संसद मार्ग), खुर्शीद भवन (जनपथ रोड), सैंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल फ्लैट्स (पेशवा रोड), कर्जन रोड एपार्टमेंट्स यूथ होस्टल (जनपथ), हिमाचल भवन (कालेज रोड), विश्व स्वास्थ्य संगठन भवन (रिंग रोड), आकाशवाणी शोध विभाग (रिंग रोड), ड्रम भापे बिल्डिंग (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), केंद्रीय राजस्व भवन (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), ए जी सी आर बिल्डिंग (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), सी ए जी बिल्डिंग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भवन (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), इएसआईसी (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), दिल्ली विकास भवन (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), विकास मीनार (इंद्रप्रस्थ एस्टेट), पुलिस मुख्यालय, मानक भवन (बहादुरशाह जफर मार्ग), शक्ति सदन, विदेश डाकघर (कोटला रोड), उत्तर रेलवे लोको (मिंटो रोड), सीपीडब्ल्यूडी अपार्टमेंट्स (मिंटो रोड), इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानिंग (रिंग रोड), जीबी पंत अस्पताल, विश्वविद्यालय संगठन (कोटल रोड), उत्तर रेलवे आवासीय कालोनी (पंचकुइयां रोड), पंजाब नेशनल बैंक (संसद मार्ग), यूको बैंक भवन (संसद मार्ग), आकाशवाणी भवन, योजना भवन, एयर लाइंस हाउस (रकाबगंज गुरुद्वारा रोड), चुनाव आयोग, प्रेस ट्रस्ट भवन (संसद मार्ग), रेल भवन, कृषि भवन (रफी मार्ग), भारती भवन (डा० राजेंद्र प्रसाद रोड), लोहिया अस्पताल, सेना भवन (डुप्ले रोड), निर्माण भवन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, श्रम शक्ति भवन, विट्ठल भाई पटेल भवन, वायुसेना मुख्यालय (रफी मार्ग), परिवहन भवन, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कालेज और अस्पताल (शाहदरा), टेलीफोन एक्सचेंज (पूसा रोड), एनपीएल आवासीय फ्लैट, सीएसआईआर कांप्लैक्स (पूसा इंस्टीट्यूट), नर्सेज होस्टल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल (हरि नगर), टेलीफोन एक्सचेंज (राजौरी गार्डन), सर्जंस होस्टल (हरि नगर), अकबर होटल, वायुसेना रिकार्ड आफिस (सुब्रतो पार्क), अशोक होटल, सम्राट होटल, चाणक्य भवन (चाणक्यपुरी), वायुसेना पश्चिम कमान (गुड़गांव रोड), यशवंत पैलेस (चाणक्यपुरी), नौसेना आवासीय फ्लैट (विनय मार्ग), आर० के० पुरम बहुमंजिले आवासीय फ्लैट (सेक्टर-१३) कुतुब होटल, आईआईटी (हौज खास), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, टेलीफोन एक्सचेंज (हौजखास), वेयर हाउस निगम (इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास), राष्ट्रीय विकास निगम (इंस्टीट्यूशनल एरिया), नेशनल कोआपरेटिव यूनियन (इंस्टीट्यूशनल एरिया), विकास सदन (आईएनए मार्केट के पीछे), राष्ट्रीय शिक्षा, योजना और प्रशासन संस्थान (आईआईटी कांप्लेक्स, हौजखास), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड), सीजीओ कांप्लेक्स (लोदी एस्टेट), सेम विहार (संगम सिनेमा के सामने), सीआरआरआई बिल्डिंग (कालिंदी कालोनी), टेलीफोन एक्सचेंज (नेहरू प्लेस), रणजीत होटल।

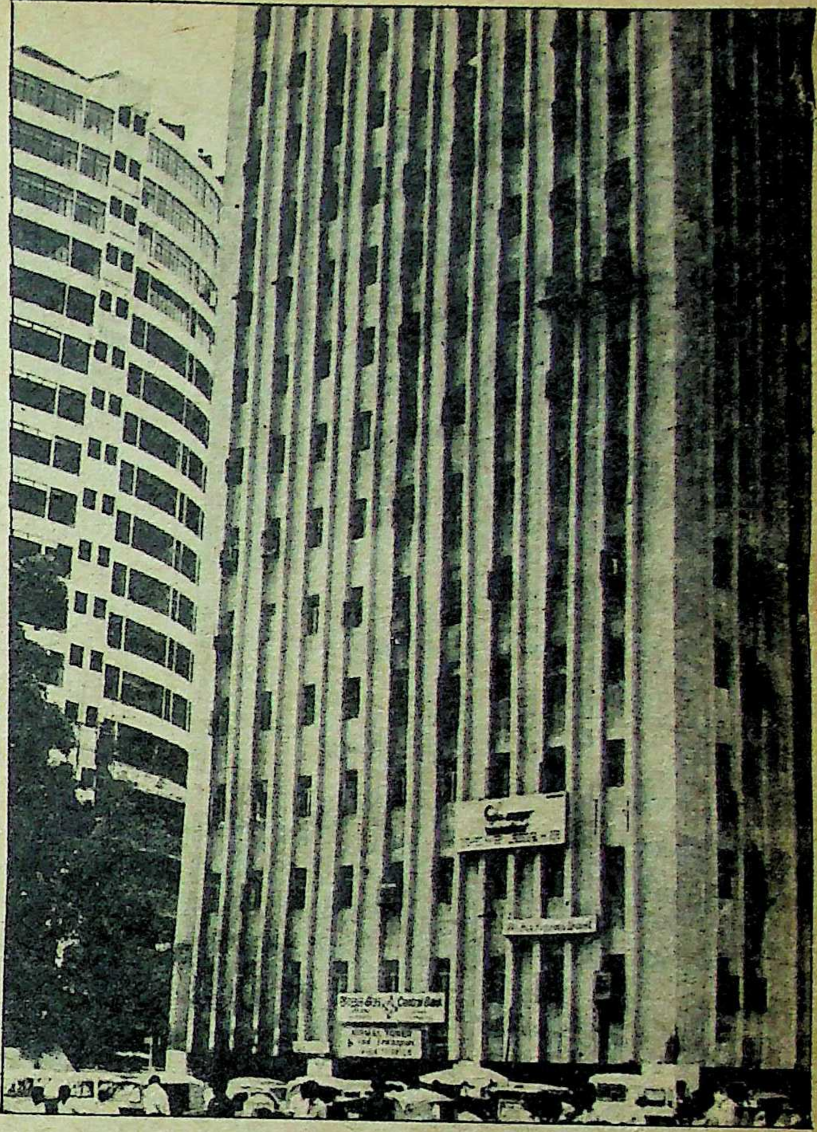

भगवान ही मालिक : कनाट प्लेस स्थित निर्मल टावर

को लेकर है। इन बहुमंजिली इमारतों को आग से बचाने के लिए दिल्ली अग्नि-निरोधक और अग्निसुरक्षा कानून, १९८६ में खास ध्यान दिया गया है। इमारतों के किसी फ्लोर, फ्लैट या हिस्से के बिकने पर भवन निर्माता अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोने की कोशिश करते हैं। कानून की धारा-२-जे में इसीलिए अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से भवन इस्तेमाल करनेवालों पर जिम्मेदारी डाली गयी है। धारा -२-जे और 'के' में किरायेदार से लेकर इस्तेमाल करनेवालों और मालिकों तक को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, पर कानूनी नोटिस अब भी बिल्डर्स और मालिकों को ही दिये जा रहे हैं।

जिस दिन अंसल भवन में आग लगी, उसी दिन यमुना किनारे आई०टी०ओ० पुल के पास २०० झुग्गियां स्वाहा हो गयीं। पूरा दमकल महकमा अंसल भवन की आग बुझाने में लग गया। ऐसे में गरीबों के आशियानों में लगी आग की सुध कौन लेता। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या दिल्ली दमकल सेवा दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है?

गोपाल टावर में आग लगे चार साल हो गये, पर दिल्ली दमकल ने ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए पूरे उपकरण अभी तक नहीं जुटाये हैं। आज दिल्ली में कई इलाकों से दमकल केन्द्र करीब १५ किलोमीटर की दूरी पर हैं। जब तक इन स्थानों पर दमकल पहुंचेंगे, सब कुछ स्वाहा हो चुका होगा। दिल्ली के करीब आधे लोग झुग्गी-झोंपड़ी, कटरों और शहरीकृत गांवों में रहते हैं। हर साल दिल्ली में हजारों झुग्गी-झोपड़ियां स्वाहा होती रहती हैं। पर सरकार इससे सकते में नहीं आती। उसकी नींद टूटती है, ऊंची इमारतों में आग लगने से। देखना है कि इस बार अंसल भवन में आग लगने से जागी सरकार कब तक जागी रहती है।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

—कुमार गिरि

पंजाब

मुख्यग्रंथी क्या कर रहे हैं ?

आतंकवादी हत्याएं बदस्तूर जारी हैं, सरकार असहाय है और पांचों मुख्यग्रंथियों में फूट पड़ी हुई है। विडम्बना यह है कि इन हत्याओं को रोकने की सदिच्छा रखनेवाले दर्शनसिंह रागी भी लाचार हैं। लोगों को धमकाने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध अकाल तख्त साहब की मोहर का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है और स्वर्ण मंदिर एक बार फिर असामाजिक तत्वों का गढ़ बन गया है। क्या ये मुख्यग्रंथी आपसी मतभेद भुलाकर स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को कायम करने और उग्रवादी तत्वों पर अंकुश लगाने की कोई कारगर कोशिश करेंगे ?

भगवान ने बचाया : लालड़ू बस हत्याकांड में दैवयोग से बचा एक शिशु। छाया : करन सिंह (ट्रिब्यून)

अभी हाल में अमृतसर स्थित भाई गुरुदास हाल में सिख संप्रदाय के पांच मुख्यग्रंथियों की एक अति गोपनीय बैठक हुई। ग्रंथियों और उनके जत्थेदारों के अलावा बैठक में उपस्थित थे, शीर्षस्थ आतंकवादी गुटों के कुछ प्रतिनिधि, जिनमें उल्लेखनीय थे 'पंथक कमेटी', 'खालिस्तान कमांडो फोर्स' व 'दमदमी टकसाल' के कुछ भूमिगत नेतागण।

आपातकालीन बैठक का मुख्य विषय था, संप्रदाय के पांच सर्वोच्च धार्मिक नेताओं के मध्य पिछले दिनों उभरे तीखे मतभेदों को दूर करना और अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार दर्शन सिंह रागी को इस्तीफा देने से रोकना।

पृष्ठभूमि : बैठक की पृष्ठभूमि में कुछ अल्पविदित तथ्य हैं जिनका उजागर होना विषय को समझने के लिए आवश्यक है। पहला, यह कि, मुख्य ग्रंथी दो स्पष्ट गुटों में विभाजित हो चुके हैं, जिनमें पहले का नेतृत्व दर्शन सिंह तथा दूसरे की अगुआई भाई कश्मीर सिंह कर रहे हैं। दूसरा, यह कि दर्शन सिंह की केन्द्र सरकार व आतंकवादियों के मध्य बातचीत कराने की रणनीति मुख्यग्रंथी कश्मीर सिंह, जसवंत सिंह व सविंदर सिंह को स्वीकार नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार से बातचीत के मुद्दों में 'खालिस्तान' भी एक हो। तीसरा, यह कि दर्शन सिंह के एकमात्र समर्थक मुख्यग्रंथी पूरन सिंह चाहते हुए भी उनका खुलकर साथ नहीं दे पा रहे हैं, जिससे दर्शन सिंह बिलकुल अकेले पड़ गये हैं और अंतिम यह कि इस दौर में 'दमदमी टकसाल' व 'पंथक कमेटी' अलिखित रूप से अकाल तख्त की 'सर्वोच्च सत्ता' से भी सर्वोपरि होती जा रही है, जिससे सिख राजनीति दो फालों में विभाजित हो गयी है। पिछले एक माह में तो हालत यहां तक पहुंच गयी थी कि 'पंथक कमेटी' अपने इश्तहारों व धमकीभरे पत्रों में अकाल तख्त का चिन्ह व मुहर खुलकर इस्तेमाल कर रही थी। स्वर्णमंदिर की परिक्रमा के चारों ओर की दीवारों पर लगा एक काला-सफेद पोस्टर अकाल तख्त की खुली अवहेलना का जीता-जागता प्रमाण है। यह पोस्टर, जिसमें पंजाब के अल्पसंख्यकों को चेतावनी दी गयी है कि उनका भारी संख्या में नरसंहार किया जायेगा, 'अकाल तख्त साहब' की गोल मोहर के साथ जारी किया गया है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति के कारण मुख्यग्रंथियों की आपातकालीन बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और ऐसा सिद्ध भी हो गया इस बात से कि दर्शन सिंह ने मीटिंग के बाद इस्तीफा देने का विचार फिलहाल छोड़ दिया है।

समझौता : अंतिम समझौता इस बात पर हुआ कि अतिवादी संगठन हरमंदिर की पवित्रता को भंग नहीं करेंगे और जवाब में दर्शन सिंह पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे 'नौजवानों' की बात हर मंच पर उठायेंगे। दर्शन सिंह ने इस बात पर भी हामी भर दी है कि वह सरकार से बातचीत तब तक नहीं करवायेंगे जब तक 'पुलिस मुकाबले' बन्द नहीं कर दिये जाते।

'दमदमी टकसाल', 'पंथक कमेटी' व उनके द्वारा समर्थित ३ मुख्यग्रंथी इस बात पर सहमत हो गये कि सिद्धांत रूप से किसी भी संगठन को यह हक नहीं दिया जायेगा कि वह ग्रंथियों का दिशा निर्देश करें। हाल में दर्शन सिंह ने अमृतसर में स्वीकार किया था कि बहुत से संगठन उन्हें स्पष्ट निर्देश जारी कर रहे थे। बहुत से टकसाली नेता भी समय-समय पर 'सुझाव' भेजने से बाज नहीं आते थे, जिससे उन्हें अपनी हैसियत एक कठपुतली की तरह नजर आती थी। दर्शन सिंह जैसे महत्वाकांक्षी धार्मिक नेता अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए समझौते तो कर सकते हैं, परंतु दूसरों की उंगलियों पर नाचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि 'सुझावों' और 'निर्देशों' के चलते हुए मतभेदों के उभरने पर उन्होंने पिछले माह के अंत में और फिर इस माह के प्रारंभ में दो बार अपना त्यागपत्र लिख भेजा था।

अकाल तख्त जत्थेदार के धार्मिक और राजनीतिक विरोधी भी यह नहीं चाहते कि वह त्यागपत्र देकर चले जायें। उनकी इस जबरदस्त साख के पीछे उनकी दुर्लभ वाक्पटुता एवं उनका पंजाब के बाहर के सिखों पर भी प्रभाव का होना है। इसके अलावा वह एक ऐसे नेता हैं जो मतभेदों से जर्जर सिख समुदाय में सभी को स्वीकार्य हैं। चाहे वह बादल-तोहड़ा हों अथवा अपदस्थ पुलिसकर्मी सिमरनजीत सिंह मान, चाहे वह कमांडो फोर्स के लाभ सिंह हों या दमदमी टकसाल के बाबा ठाकुर सिंह—कोई भी दर्शन सिंह को हटाने की बात नहीं कर रहा।

मजे की बात तो यह है कि सिखों में नरमदलीय लोग भी दर्शन सिंह को अपना नेता मानते हैं। इसीलिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री बरनाला के निकटतम सहयोगी बलवंत सिंह सहित आधे से अधिक अकाली गुप्त रूप से दर्शन सिंह से मिलकर अवश्य आये। मुख्यमंत्री बरनाला की बरखास्तगी के बाद भी अकालियों का दर्शन सिंह के पास आना बदस्तूर जारी है।

दर्शन सिंह की स्थिति : यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि केन्द्र और राज्य सरकारें भी दर्शन सिंह के प्रभाव

कौन रोकेगा ये हत्याएं : चण्डीगढ़ अस्पताल में भाग्यहीन बस यात्रियों के शव छाया : करन सिंह (ट्रिब्यून)

से मुक्त नहीं हैं। यही कारण है कि तीन बार गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद भी दर्शन सिंह को गिरफ्तार करने की 'गलती' राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी नहीं की गयी। उनके खिलाफ जारी अंतिम गैर-जमानती वारंट वापस करने की अंतिम तिथि अभी गत ८ जुलाई को ही निकली है।

इतनी साख व अविवादास्पदता के बावजूद क्या कारण है कि अन्य मुख्य ग्रंथी दर्शन सिंह के खिलाफ कांटे बो रहे हैं? दरअसल उन्हें चिढ़ है, दर्शन सिंह के फार्मूले से, जिसके अंतर्गत वह पंजाब में शांति कायम करना चाहते हैं। अकाल तख्त के मुखिया ने अपनी नीति और राजनीति फिल्मी-हस्ती सुनील दत्त और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के गैर-सरकारी दूत जैनमुनि सुशील कुमार से अपनी बातचीत में बिलकुल स्पष्ट कर दी थी।

उन्होंने तीन मुख्य मांगें रखी थीं, जिनके माने जाने पर बातचीत की जा सकती है। पहली, जोधपुर सहित देश की समस्त जेलों में कैद राजनीतिक बन्दी तुरंत छोड़े जायें। दूसरी, बैरकें छोड़नेवाले फौजी (उनकी भाषा में धर्मी फौजी) बहाल किये जायें और तीसरी, पुलिस द्वारा सारे पंजाब के गांवों में किये जा रहे 'पुलिस मुकाबले' बन्द किये जायें।

दरअसल गौर से देखा जाये, तो इन तीन मांगों के द्वारा दर्शन सिंह ने बड़े सुलभ चातुर्य से सिख समाज के सभी प्रमुख तबकों को खुश कर दिया। कैदियों के छोड़ने में बादल-तोहड़ा तथा सिमरनजीत सिंह मान के अलावा अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के तमाम नेताओं को एकदम फायदा पहुंचेगा। फौजियों की बहाली व जोधपुर जेलों में बन्द लोगों की रिहाई से पंजाब की आम जनता खुश होगी तथा पुलिस मुकाबले बन्द होने से अतिवादी और आतंकवादी युवक उनके पीछे हो लेंगे।

वर्चस्व किसका : परंतु एक अन्य दृष्टि से इस फार्मूले में एक संकट भी कैद है, जो अन्य ग्रंथियों को परेशान किये हुए है। वह यह कि अंततोगत्वा यह सब पंजाब में शांति लाने के लिए किया जा रहा है, जिसे 'पंथक कमेटी और दमदमी टकसाल चलानेवाले व उनके आका कतई नहीं चाहते। उन्हें तो 'खालिस्तान' चाहिए, जिसकी नींव अशांति, वैमनस्य और दंगों पर ही रखी जा सकती है। मुख्यग्रंथियों के बीच आपसी मनमुटाव का दूसरा कारण यह है कि दर्शन सिंह और उनके सहयोगी पूरन सिंह अकाल तख्त को सर्वोच्च मानते हैं जो सिख धर्म की रवाइयात के अनुकूल है। उन्होंने यह मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया है कि 'पंथक कमेटी' कभी भी किसी भी ग्रंथी को निकाल बाहर कर सकती है। दरअसल 'पंथक कमेटी' ने पिछले सरबत खालसा में (२६ जनवरी, १९८७ को) जनमत के नाम पर मौजूद छोटे से समूह के सामने प्रस्ताव रखा था कि उसे यह अधिकार दिया जाये कि अकाल तख्त के ग्रंथियों पर नजर रखे और 'काम सही तरह' न करने की स्थिति में उन्हें हटा सके। इससे पहले कि स्वर्णमंदिर में उपस्थित लोग (जिनमें से अधिकांश जेलों में बन्द व पिछले सालों मारे गये सिखों के रिश्तेदार आदि हैं) अपनी राय रखते, 'बोले सौ निहाल' के नारों में प्रस्ताव को अनुमोदित मान लिया गया।

अतएव अन्य तीन ग्रंथी यह मानते हैं कि उन्हें जनमत के समक्ष झुकना चाहिए और जब भी पंथक कमेटी कहे अकाल तख्त के उच्च पद से हट जाना चाहिए। परंतु जाहिर है, ऐसे आज्ञाकारी अनुयाइयों को पंथक कमेटी हरगिज नहीं हटायेगी। उनकी आंखों के कांटे तो दर्शन सिंह व कुछ हद तक पूरन सिंह हैं जो अकाल तख्त को सर्वोच्च मानते हैं और सिखों के धर्म तथा दर्शन की दुहाई बात-बात पर देते हैं।

पिछले सप्ताह हुई घटनाओं, आपसी झगड़ों और अंततः दर्शन सिंह के तदर्थ इस्तीफे से मुख्यग्रंथियों के मतभेद चरम सीमा पर पहुंच गये। इसका परिणाम यह हुआ कि मौजूदा संकट से पंथ को उबारने के लिए 'पंथक कमेटी' व 'दमदमी-टकसाल' की पहल पर तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलायी गयी।

तमाम मुख्य मुद्दों के अलावा इसमें यह भी विचार किया गया कि दरबार साहब परिसर से सिख या हिन्दू व्यापारियों को पैसे के लिए धमकी-भरे पत्र लिखा जाना कहां तक जायज है? दर्शन सिंह व उनके सहयोगियों का मानना है कि परिसर में पुलिस घुसने का एक कारण ये धमकी भरे पत्र भी हैं।

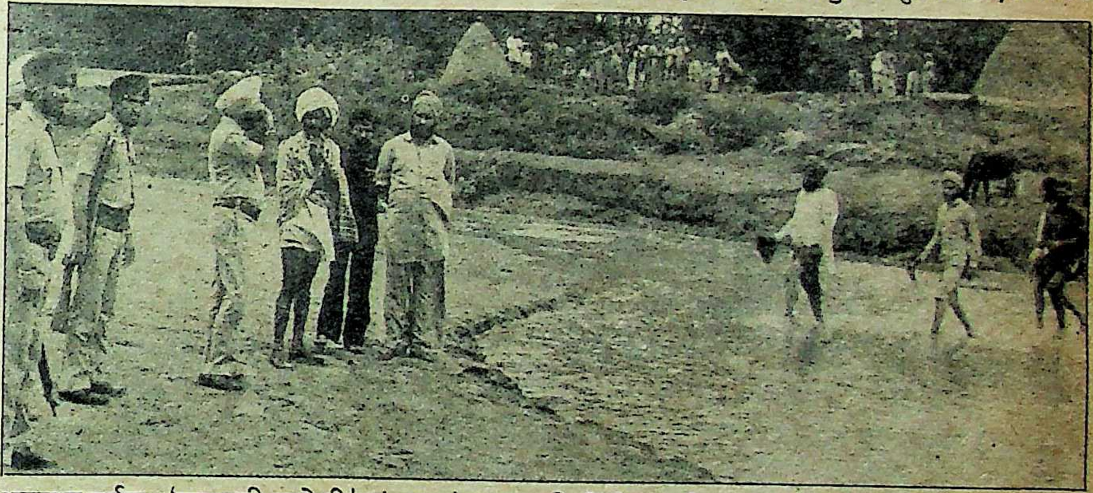

असहाय दर्शक : 'सूरत की मनोली' गांव, जहां बस यात्रियों के हत्यारे बरसाती नाले के कारण अपने एक मृत साथी को कार सहित छोड़ गये थे। छाया : योग जॉय (ट्रिब्यून)

फिलहाल दोनों पक्ष यह मान गये हैं कि आगे ऐसे पत्र दरबार साहब परिसर से नहीं लिखे जायेंगे और परिक्रमा में पोस्टर भी नहीं लगाये जायेंगे। स्वर्ण मंदिर की राजनीति के जानकार सूत्रों के अनुसार पंथक कमेटी यह मान गयी है कि धमकी भरे पोस्टरों से हरमंदिर साहब में भक्तों का आना कम हुआ है, जिससे शिरोमणि कमेटी की आय बहुत घट गयी है।

आज की स्थिति में, कम-से-कम गत मीटिंग के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यग्रंथियों के मतभेद समाप्त हो गये हैं। परंतु पंजाब के राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि ऐसा सिर्फ सतह पर ही हुआ है। कब, कौन से मोड़ पर ये मतभेद पुनः उभरकर सामने आ जायें और नये मुख्यग्रंथी रखने की नौबत आ जाये, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस बात में कोई संदेह नहीं कि आगे आनेवाली धार्मिक सत्ता 'कठपुतलियों के राजदरबार' से अधिक कुछ नहीं होगी।

—विमुख सिंह

ऋषिकेश

आतंकवादी तो यही चाहते थे...?

आतंकवादियों द्वारा ७६ बस यात्रियों के नृशंस नरसंहार की सबसे घृणित प्रतिक्रिया ऋषिकेश में हुई। ऐसी आशंका उसी समय बन गयी थी, जब यह हादसा हुआ। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ऋषिकेश में जुनून को रोक पाने में असफल रहा। एक समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्या करके पंजाब के बाहर के सिखों के प्रति नफरत फैलाने की आतंकवादियों की साजिश को विफल करने के लिए यदि एहतियात बरता जाता, तो क्या ऋषिकेश में हिंसक घटनाएं होतीं ? ऋषिकेश से सुरेश द्विवेदी की रिपोर्ट :

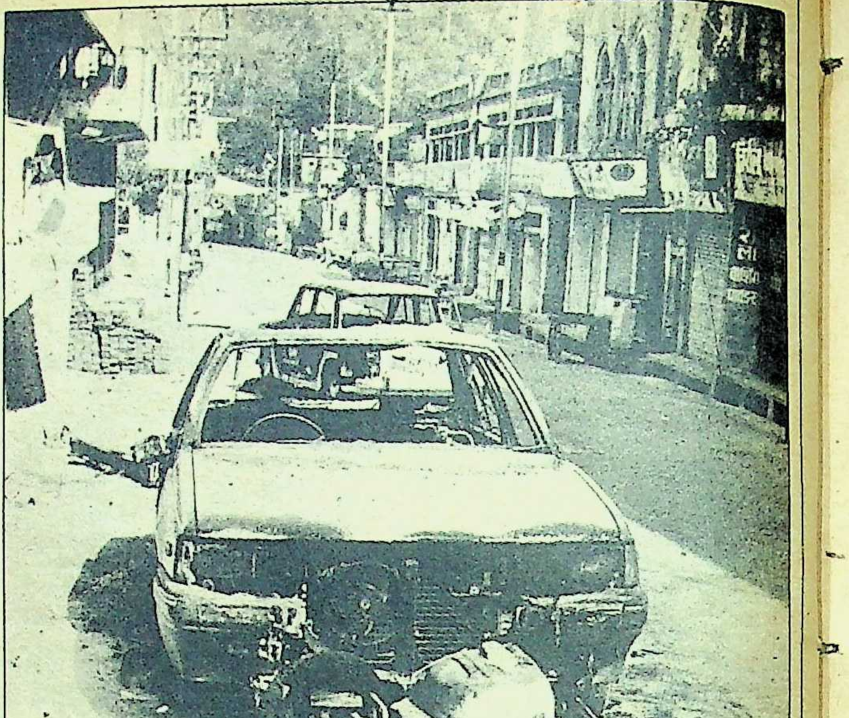
सांप्रदायिकता की आग में झुलसे वाहन

छाया : मनमोहन शर्मा

आतंकवादी तो चाहते ही हैं कि भारत एक बार फिर १९८४ की ओर लौट जाये, ताकि पंजाब से बाहर रह रहे निर्दोष सिखों के खिलाफ हिंसा भड़के और वे पंजाब की ओर दौड़ने के लिए बाध्य हो जायें तथा देश में अस्थिरता के बादल और छा जायें। ६-७ जुलाई को लालड़ू और दरियापुर में तीन बसों के यात्रियों की हत्या के पीछे आतंकवादियों का यही नापाक इरादा था, तभी तो ७६ निर्दोष लोगों को असमय मौत की सजा दे दी गयी। लालड़ू कांड में (जिसमें ४० लोगों की मौत हुई और ज्यादातर यात्री गढ़वाली थे) आतकवादियों ने उन्हीं लोगों को मौत की नींद सुलाया, जो गैरसिख थे।

इस कांड की हिंसक प्रतिक्रिया की आशंका थी, क्योंकि पंजाब में जब भी आतंकवादियों ने वीभत्स कार्य किया, उसकी निंदा के लिए उत्तर भारत में बंद और प्रदर्शन का दौर चला है। इस बार भी लालड़ू और दरियापुर कांड की निंदा के लिए उत्तर भारत के कई शहरों में बंद और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। सभी को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के अमन-चैन वाले और धार्मिक शहर ऋषिकेश में लालड़ू-कांड की प्रतिक्रिया गंभीर रूप धारण कर सकती है; क्योंकि यहां के अधिसंख्य लोगों को आतंकवादियों की गोली का शिकार होना पड़ा था। जब आशंकाएं पनप रही थीं, तो ऋषिकेश शहर का प्रशासन कैसे सोया हुआ था, जबकि उसे सबसे अधिक सचेत होना चाहिए था। ७ जुलाई की सुबह से ही तनाव और ८ जुलाई को भड़के दंगे को १९८४ का 'रीप्ले' कहा जा सकता है। आतंकवादियों द्वारा नरसंहार की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी तथा उत्तराखण्ड मोर्चे के आह्वान और व्यक्तिगत स्तर पर उपजे रोष, एवं शोक संवेदना के तहत ८ जुलाई को उत्तर भारत के अन्य शहरों की तरह ऋषिकेश में भी 'बंद' की घोषणा की गयी थी। यह बंद पूरी तरह स्वेच्छित था। बाजार बंदी के साथ ही सरकारी-गैरसरकारी वाहनों का चक्का जाम था। सिखों ने भी सद्भावना जतायी। कुछेक को छोड़कर अधिकांश ने अपनी दूकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा था।

नरसंहार के विरुद्ध आक्रोशित भीड़ सड़कों पर थी, लेकिन हिंसा के कोई आसार दोपहर १२ बजे तक परिलक्षित नहीं हुए थे, लेकिन लक्ष्मण झूला मार्ग पर स्थित एक धार्मिक स्थान से हुए शस्त्रों के प्रदर्शन ने माहौल बिगाड़ दिया। उत्तेजित भीड़ इस धार्मिक स्थल के सामने एकत्र होने लगी। अफवाहों ने आग में घी का काम किया। इसी बीच धर्मस्थल के अंदर से बाहर खड़ी भीड़ पर फायरिंग होने लगी। पहली ही गोली ने एक को मौत के घाट उतार दिया। इसी के बाद यह तीर्थस्थली हिंसा की चपेट में आ गयी। पुलिस फोर्स की कमी और प्रशासनिक अक्षमता के कारण बेलगाम हुई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और खून-खराबे पर उतारू हो गयी। स्थिति पर काबू न होते देख स्थानीय मजिस्ट्रेट ने बदहवासी में पुलिस को गोली चलाने का हुक्म दे डाला। फलस्वरूप स्थिति बद से बदतर हो चली। गंभीरतम होती जा रही स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारी आर०पी० अरोड़ा ने ८ किलोमीटर दूर रायवाला स्थित सैनिक छावनी में गुहार लगायी। शाम ४ बजे जब सेना की एक कंपनी ने ऋषिकेश में प्रवेश किया तब तक इस तीर्थस्थली की 'श्री' उजड़ चुकी थी। सेना के जवानों ने उस धार्मिक इमारत को अपने घेरे में ले लिया, जिसके सामने हिंसा की सांप्रदायिक मोर्चाबंदी चल रही थी। शाम तक यहां पहुंची पुलिस और पी०ए०सी० की अतिरिक्त फोर्स ने किसी प्रकार इस शहर की बची-खुची संपत्ति को बचा लिया। हिंसा के इस दौर में ५ लोगों की जानें गयीं। शहर की ३६ जगहों पर एक संप्रदाय विशेष की दूकानों और प्रतिष्ठानों पर की गयी आगजनी और तोड़-फोड़ में लगभग ३ लाख की संपत्ति हिंसा की भेंट चढ़ गयी। लगभग २० व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें १३ को गोली के छर्रे लगे थे। ये गोलियां उस धार्मिक स्थल से भीड़ पर चलायी गयी बतायी गयीं।

ऋषिकेश में उपजा यह हिंसक उन्माद सहज ही नहीं था। ६ जुलाई को आतंकवादियों ने लालड़ू (पटियाला) के पास हरियाणा रोडवेज की जिस बस के ४० लोगों को गोलियों से भून डाला था, उनमें अधिकांशतः गढ़वाल परिक्षेत्र के थे। गढ़वाल परिक्षेत्र में ही आनेवाले ऋषिकेश में इस नरसंहार की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। प्रशासन को भी उसी रात मृतकों के बारे में जानकारी मिल गयी थी। ७ जुलाई को भारतीय जनता पार्टी तथा उत्तराखंड मोर्चे की स्थानीय इकाई ने अगले दिन ८ जुलाई को नरसंहार की प्रतिक्रिया स्वरूप बंद की अपील की। उसी रात सामाजिक और

राजनीतिक नेताओं ने प्रशासन के साथ बैठक कर 'बंद' के दौरान जुलूस या सभा का आयोजन न करने तथा सद्भावना बनाये रखने का निर्णय किया था। इस बैठक में एकीकरण समिति तथा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, जगमोहन सकलानी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, रामप्रकाश कालरा, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हरिमोहन गुलाटी, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, वीरेंद्र शर्मा सहित हेमकुंड गुरुद्वारा के ट्रस्टी, सरदार गुरुबख्श सिंह बिंद्रा शामिल हुए थे। इन लोगों ने एहतियाती तौर पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग भी आवासीय मजिस्ट्रेट आर०पी० अरोड़ा से की थी।

अगले दिन बंद के दौरान जब हेमकुंड स्थित धार्मिक स्थल से गोली चलने पर उत्तेजना भड़की, उस समय फोर्स के नाम पर शहर में थाने के ३६ पुलिस जनों के अतिरिक्त मात्र एक प्लाटून पी०ए०सी० मौजूद थी। यह फोर्स भी शहर के विभिन्न भागों में एक-एक, दो-दो की संख्या में फैली हुई थी। आवासीय मजिस्ट्रेट आर०पी० अरोड़ा, पुलिस का एक दल साथ लेकर शहर में भटक रहे थे। प्रदेश युवक कांग्रेस के संयुक्त मंत्री हर्षवर्धन के अनुसार, "जिस समय लक्ष्मण झूला मार्ग पर स्थित हेमकुंड धार्मिक स्थल के सामने स्थिति बिगड़ी उसी समय मैंने मजिस्ट्रेट श्री अरोड़ा को सूचित किया था। इस जानकारी के बावजूद वह फोर्स लेकर वहां पहुंचने के बजाय कोतवाली में जाकर बैठ गये थे।"

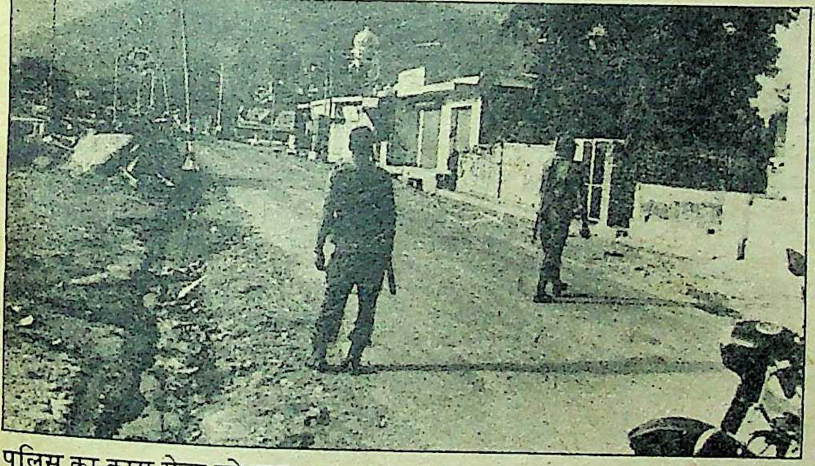
पुलिस का काम सेना को करना पडा।

छाया : मनमोहन शर्मा सरदार सोहन सिंह

पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह ने स्थिति संभालने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन फोर्स की कमी के कारण वह सफल नहीं हो सके थे। स्थिति जब बेकाबू हो गयी, तब लोगों ने कोतवाली में बैठे आवासीय मजिस्ट्रेट श्री अरोड़ा का घेराव किया। तब कहीं जाकर उन्होंने सक्रियता दिखायी और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को गोली चलाने के आदेश दिये और शहर में कर्फ्यू की घोषणा की। लेकिन तब तक इस तीर्थस्थल का शांतिपूर्ण वातावरण पूरी तरह अशांत हो चुका था।

इस संबंध में आवासीय मजिस्ट्रेट आर०पी० अरोड़ा का कहना था, "मैंने ७ जुलाई की शाम ही जिला प्रशासन से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी, लेकिन पता नहीं क्यों फोर्स समय से यहां नहीं पहुंच सकी।" इसके विपरीत यहां पहुंचे अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) एम०आर० कुकरेती का कहना था, "८ जुलाई को यहां स्थिति बिगड़ने के बाद अतिरिक्त फोर्स की मांग स्थानीय स्तर पर की गयी थी। यही वजह थी कि फोर्स यहां हिंसा के बाद पहुंची।"

ऋषिकेश के इंका विधायक किशोरी लाल सकलानी का कहना था, "यह सब प्रशासनिक अक्षमता और पुलिस फोर्स की कमी के कारण हुआ।"

भारतीय जनता पार्टी के शहर इकाई के अध्यक्ष इंदुसेन अग्रवाल का आरोप था, "ऋषिकेश में हुई सांप्रदायिक वारदात यहां के आवासीय मजिस्ट्रेट आर०पी० अरोड़ा की लापरवाही का नतीजा थीं।"

प्रशासन पर हिंसक घटनाओं के बाद भी लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप हैं। युवक कांग्रेस शहर इकाई के अध्यक्ष जगमोहन सकलानी का कहना था, "प्रशासन ने उस धार्मिक स्थल की तलाशी न लेकर घोर लापरवाही का परिचय दिया था। घटना के समय उस धार्मिक स्थल में बने अतिथि-गृह में लगभग ५०० लोग उपस्थित थे। हालांकि वे एक संप्रदाय-विशेष के तीर्थयात्री थे, लेकिन पुलिस ने उनकी तलाशी लिए बगैर उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर भिजवा दिया था।"

जन-आक्रोश को देखते हुए अगले दिन ९ जुलाई की दोपहर अतिरिक्त जिलाधिकारी, एम०आर० कुकरेती, आवासीय मजिस्ट्रेट, आर०पी० अरोड़ा ने पुलिस तथा सेना की मदद से हेमकुंड स्थित उस धार्मिक स्थल की तलाशी ली, जहां से भीड़ पर गोलियां बरसायी गयी थीं। तलाशी के दौरान मिली एक दोनाली बंदूक तथा १३ तलवारों को जब्त कर लिया गया। बरामद बंदूक वहां के प्रबंधक सरदार सोहन सिंह की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तेजित भीड़ से घबराकर उन्होंने अपनी इस बंदूक से आत्मरक्षार्थ फायर किये थे।

ऋषिकेश के नागरिकों में प्रशासन के प्रति इस बात को लेकर भी रोष था कि सरदार सोहन सिंह को गोली चलाने की स्वीकारोक्ति के बावजूद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हरि मोहन गुलाटी ने बताया, "स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ तथा कुछ अन्य स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के विरुद्ध पुलिस का साथ देने वालों को ही बंदी बनाया गया। प्रशासन ने हिंदू और सिखों के बीच रही-सही सद्भावना भी समाप्त कर दी थी।" उनका कहना था, "पुलिस ने उस धार्मिक स्थल से मात्र एक बंदूक बरामद की। वहां से चली गोलियों से १३ लोग जख्मी हुए थे। उस धार्मिक स्थल से जिस तरह गोलियां चलीं, उससे यह बात गले नहीं उतरती कि एक ही बंदूक से तावड़तोड़ इतनी गोलियां चली होंगी। प्रशासन को उसी समय तलाशी लेनी चाहिए थी। ९ जुलाई की सुबह ५ बजे वहां मौजूद लोगों को उनकी ५ बसों के जरिये पी०ए०सी० की २ प्लाटूनों के साथ प्रशासन ने उन्हें यहां से सुरक्षित तो भिजवा दिया, लेकिन उनकी तलाशी की अहमियत नहीं समझी गयी।"

प्रशासन की एक कमी यह भी रही कि पत्रकारों के समक्ष वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने से हर अधिकारी कतराता रहा। आवासीय मजिस्ट्रेट श्री अरोड़ा ने पत्रकारों के समक्ष मौन साध लिया था। नतीजतन, पत्रकारों ने अफवाहों को अपने समाचार में समाहित कर लिया। यह भी एक संयोग ही है कि जहां प्रशासन ने उदासीनता बरती वहीं कुछेक पत्रकारों ने भी अपना विवेक खो दिया था। एक समाचार पत्र के संवाददाता ने यह समाचार प्रकाशित करा कर सनसनी फैला दी कि उस धार्मिक स्थल से टिहरी के पुलिस अधीक्षक (नाम देते हुए) ने भीड़ पर गोलियां चलायी थीं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस संवाददाता ने समाचार देने से पूर्व यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि टिहरी के पुलिस अधीक्षक किस जाति के हैं? बाद में जिलाधिकारी ने इस गैर-जिम्मेदाराना समाचार का खण्डन किया।

इस अप्रत्याशित घटना ने ऋषिकेश के आपसी सौहार्द में वैमनस्यता का जहर घोल दिया है। काली-कमली मार्ग पर गोल मार्किट में स्थित अपनी जली हुई टालों के समक्ष गमगीन खड़े सरदार इंदर सिंह, हरनेक सिंह और दिलीप सिंह का कहना था, "हमें अपने नुकसान का उतना दुख नहीं जितना कि इस बात का है कि यहां भी सांप्रदायिक कटुता की भावना उपज गई है।" उनका कहना था, "आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, जब कि हमारी एक जाति है। ऋषिकेश में जो कुछ भी हुआ, सब अचानक हुआ। हमारे धार्मिक स्थल में बाहर से आकर उतरे तीर्थयात्रियों ने जो कुछ किया, वह उनकी घबराहट और भय का परिणाम था। वे यहां की सांप्रदायिक एकता से नावाकिफ थे।"

हेमकुंड धार्मिक स्थल के बाहर तैनात सेना के जवानों की प्रतिक्रिया थी, "यह पुलिस की निष्क्रियता का ही नतीजा है कि हमें अब उनकी ड्यूटी निभानी पड़ती है।" इन जवानों का नेतृत्व करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था, "यह कैसी विडंबना है कि देश की सीमा पर दुश्मनों से भिड़नेवाली फौज को अब देश में ही मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है।"

फिलहाल, ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों की आमदरफ्त अब सहमी हुई है। इस तीर्थस्थली में धूनी रमाये ध्यानमग्न साधु-संन्यासियों की भाव-भंगिमाओं को इस घटना ने विचलित कर दिया है। पावन गंगा के तट और ऊंचे पर्वतों की गोद में बसी इस तीर्थस्थली की शांति कब और किस समय भंग हो जाये, नहीं कहा जा सकता। ■

सैन्य गुप्तचरी का अंतरराष्ट्रीय जाल

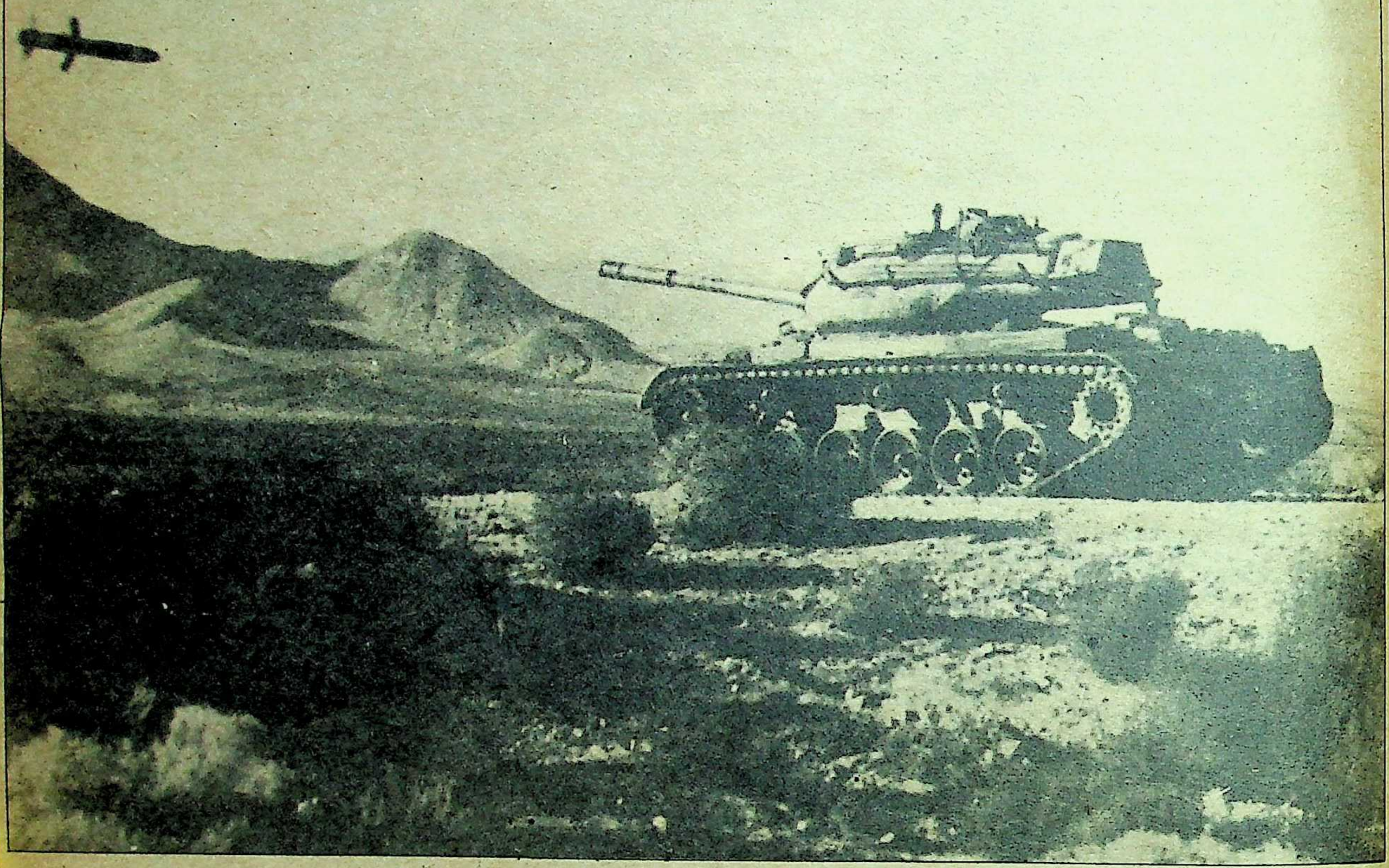

अमरीका भारत को 'सुपर कंप्यूटर' बेचने में आनाकानी क्यों कर रहा है? उसके इस भय में कितना दम है कि भारत को बेची जानेवाली उच्च संवेदनशील तकनीकी जानकारियां सोवियत रूस के हाथों में पड़ जाती हैं। रक्षा-प्रतिष्ठानों में चल रही 'अंतरराष्ट्रीय गुप्तचरी' से अपने तकनीकी ज्ञान को बचाकर रखने और दूसरे के तकनीकी ज्ञान को चुरा लेने के लिए दोनों महाशक्तियां—रूस और अमरीका—कैसी-कैसी चालें चल रहे हैं?

नये हथियारों के निर्माण की तकनीक हासिल करने के लिए सामान्यतः यही तरीका अपनाया जाता है कि यदि कोई देश इसे खरीद नहीं सकता या स्वयं इसका विकास नहीं कर सकता, तो वह इसे चुरा लेता है। सोवियत रूस ने परमाणु बम बनाने के रहस्य चोरी से प्राप्त किये थे, इजरायलियों ने भी मिराज लड़ाकू विमान का खाका चुराकर उसके अनुसार फीर-बमवर्षक नाम से अपना युद्धक विमान विकसित किया था। इसी प्रकार पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक ए०क्यू० खान ने हालैण्ड की परमाणु तकनीक को अवैध ढंग से प्राप्त करने में सफलता पा ली थी। इस जानकारी का उपयोग वह पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार तैयार करने में कर रहे हैं। इसलिए आज हर देश अपनी तकनीकी जानकारियों को गोपनीय बनाये रखने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन इधर अमरीका ने तो पूर्वी और पश्चिमी देशों से अपने संबंधों में 'तकनीकी मामलों की सुरक्षा' को एक अहम मुद्दा बना दिया है।

रीगन प्रशासन की मान्यता रही है कि सोवियत रूस के हथियारों की संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता बढ़ाकर ही किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक अमरीका ने अपने हथियारों को जिस इलेक्ट्रानिक एवं अन्य पद्धतियों से अधिक बेहतर बना दिया था—ऐसा माना जाता था कि वह पद्धतियां विकसित करने में सोवियत रूस को काफी समय लग जायेगा। लेकिन आज रूस द्वारा पश्चिमी तकनीक हासिल करने के लिए छेड़े गये महाभियान के कारण यह अंतर कम हो गया है।

रूसी गुप्तचरी : पश्चिमी तकनीक हासिल करने के लिए सोवियत रूस ने कई तरीके अपनाये हैं। पहले तरीके के अंतर्गत वह जानकारियों के खुले स्रोतों से तकनीकी जानकारियां एकत्र करता है, जो पश्चिमी देशों की तकनीकी और व्यापारिक पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित होती हैं। इन जानकारियों का बारीकी से अध्ययन करके सोवियत रूस ने कुछ मनचाही तकनीकी जानकारियां हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली है। दूसरे तरीके के अंतर्गत रूस पश्चिमी मुल्कों से गैरफौजी उपयोग के नाम पर ऐसी तकनीकी जानकारियां खरीदता है, जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सके। उदाहरण के तौर पर सत्तर के दशक के मध्य में रूस ने अमरीका से अत्यंत कठोर बाल बियरिंग तराशने की मशीनें खरीदी थीं। इन मशीनों का इस्तेमाल बाद में अत्यंत उन्नत किस्म

के बियरिंग का निर्माण करने में किया गया, जिससे उसके अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की क्षमता काफी बढ़ गयी। इधर सोवियत रूस अमरीकी कंपनियों से चिकित्सा और खनिज संबंधी शोधों के लिए कुछ उपकरण खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये भी ऐसे उपकरण हैं, जिनका दोहरा इस्तेमाल करना संभव है। मसलन रूस वहां से केट (सीएटी) विश्लेषक, अतिस्वन उपकरण और भूगर्भीय कंपन मापक यंत्र खरीदने की फिराक में है, जिससे वह इन उपकरणों में प्रयुक्त तकनीक के जरिये ध्वनि तरंगों से संबंधित ऐसे उपकरण विकसित कर सकता है जो न केवल उसकी युद्धक पनडुब्बियों, बल्कि उसके अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता को बेहद बढ़ा देंगे, साथ ही अमरीकी प्रक्षेपास्त्रों के लिए खतरा बढ़ जायेगा।

सोवियत रूस ने बड़े पैमाने पर उद्योगों से संबंधित पश्चिमी तकनीकी जानकारियां हासिल करने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। १९८५ में फ्रांस के एक दैनिक 'ले मोण्ड' ने फ्रांस की एक प्रतिगुप्तचर-रिपोर्ट के हवाले से यह रहस्योद्घाटन किया था कि सोवियत रूस पश्चिमी तकनीक हासिल करने में किस हद तक सफल रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि १९७९ में सोवियत उड्डयन उद्योग मंत्रालय को १५६ नमूने प्राप्त हुए थे और ३८९६ तकनीकी दस्तावेज उसने चोरी से हासिल किये थे। इनमें से उसने ८७ नमूनों और ३४६ दस्तावेजों का इस्तेमाल नये युद्धक उपकरणों को विकसित करने में किया था। इन जानकारियों के जरिये उसने अपने मिग-२९ और सू-२७ युद्धक विमानों के गणक-कंप्यूटर, संकेत प्रक्रिया और ईंधन व्यवस्था को विकसित किया। मेकडानेल डगलस एफ-१८ युद्धक विमान के राडार का खाका हासिल करके उसने इसकी नकल तैयार की, जिसे उसने अपने मिग-२९ लड़ाकू विमान में फिट कर दिया। अमरीका के युद्धक विमान तकनीकी श्रेष्ठता के कारण रूसी युद्धक विमानों पर पहले भारी पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही।

सोवियत रूस ने हाल ही में एक ऐसी पद्धति का विकास किया है जो युद्धपोतों से छोड़े जानेवाले प्रक्षेपास्त्रों की नीची और लंबी दूरी की उड़ानों का मार्गदर्शन करता है। यह पद्धति इन प्रक्षेपास्त्रों के उड़ान-पथ को निष्कंटक बनाती है। सोवियत रूस की तकनीकी गुप्तचरी का सबसे बड़ा कमाल तो था अमरीका के अंतरिक्ष शटल का योजना-प्रारूप हासिल कर लेना। बहरहाल, सोवियत गुप्तचरी सिर्फ उड्डयन उद्योग तक ही सीमित नहीं है। नौसैनिक क्षेत्र में भी सोवियत रूस ने विमानवाही युद्धपोतों के प्रक्षेपों का नक्शा और पनडुब्बियों के इंजन की आवाज कम करने की तकनीक प्राप्त कर ली है। युद्धक्षेत्र में काम आनेवाले हथियार मसलन टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, कापरहेडलेसर नियंत्रित तोप के गोले और कंधों से छोड़े जाने वाले विमान-भेदक प्रक्षेपास्त्र के तकनीकी रहस्य तो रूस के हाथ में पड़ ही चुके हैं। इन जानकारियों का उपयोग रूस ने या तो वैसे ही उपकरण और हथियार बनाने में किया अथवा इनके आधार पर अमरीका के मुकाबले के उपकरण और हथियार बनाये।

अमरीका के जवाबी कदम : पश्चिमी तकनीक हासिल करने के सोवियत प्रयत्नों को देखते हुए अमरीका ने भी संवेदनशील जानकारियों को गोपनीय बनाये रखने के लिए बहुपक्षीय कदम उठाये हैं। ये जानकारियां गलत हाथों में न पड़ें, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर वह 'निर्यात नियंत्रक समन्वय समिति' (कोकोम-सीओ सीओएम) का प्रयोग कर रहा है। इस समिति में अमरीका-जापान के साथ-साथ नाटो संधि से जुड़े १३ अन्य मुल्क भी शामिल हैं। इस समिति को यह कार्य दिया गया है कि वह उन सभी सैन्य संबंधी तकनीकी जानकारियों की सूची बनाये, जिनका बाहर जाना उचित नहीं है। इस समिति के सदस्य देशों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इन जानकारियों के अवैध निर्यात को नियंत्रित करने में मिलजुलकर कार्य करें। बहरहाल, इस समिति का रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इस समिति के फैसलों और निर्देशों को मानने के लिए इसके सदस्य देश बाध्य नहीं हैं, दूसरे, इस समिति के पास कार्यान्वयन शक्तियां भी नहीं हैं।

घरेलू मोर्चे पर अमरीका के विभिन्न सरकारी विभाग अपनी तकनीकी जानकारियों को गुप्त रखने के लिए सक्रिय हैं। अमरीका के विदेश विभाग ने ऐसे हथियारों की सूची जारी की है, जिनका बिना लायसेंस के निर्यात वर्जित कर दिया गया है। इसी प्रकार अमरीका के वाणिज्य विभाग ने ऐसी वस्तुओं की सूची बना रखी है, जिनमें प्रयुक्त तकनीक का दोहरा इस्तेमाल संभव है। ये वस्तुएं भी बिना वाणिज्य विभाग की स्वीकृति के निर्यात नहीं की जा सकतीं। लेकिन इन उपायों को अपर्याप्त मानकर रीगन सरकार ने १९८५ में डिफेंस टेक्नालाजी सिक्यूरिटी एजेंसी (डीटीएसए) की स्थापना की। तभी से यह एजेंसी अमरीका से निर्यात होनेवाली ऐसी हर वस्तु पर बारीक नजर रखती है, जिनका दोहरा इस्तेमाल हो सकता है। इस एजेंसी ने दावा किया है कि हथियारों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आये आवेदन-पत्रों की जांच करने के बाद उसने सोवियत रूस द्वारा खरीदे जानेवाले कुछ ऐसे उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाने में सफलता पायी है, जो यदि रूस को मिल जाते, तो उसके शोध आदि पर खर्च होनेवाले ४.६ अरब से १२ अरब रुपए तक बच जाते।

मतभेद : रीगन प्रशासन इस बात से संतुष्ट है कि उसकी 'तकनीक सुरक्षा नीति' कारगर कार्य कर रही है, लेकिन उसके आलोचक मानते हैं कि इस नीति से अमरीकी हितों को ही नुकसान पहुंच रहा है। अमरीका की एक प्रतिष्ठित संस्था 'अमेरिकन नेशनल एकेडेमी' द्वारा स्थापित जांच समिति ने दावा किया है कि तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करने की इस नीति से अमरीकी अर्थतंत्र को प्रतिवर्ष ९ अरब डालर का नुकसान होता है। इससे बुरी स्थिति यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और पुख्ता बनाने पर ध्यान दिये बगैर यह नुकसान उठाया जा रहा है। नाटो संधि से जुड़े देश और जापान, ऐसे उपकरणों की बिना लायसेंस के बिक्री कर सकते हैं, जिनके निर्यात पर अमरीका की निर्यात नियंत्रक नीतियों ने कड़े अंकुश लगा रखे हैं। इससे अमरीका के निर्यात व्यापार को जबरदस्त चोट पहुंच रही है। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात नियंत्रण नीतियों की वजह से अमरीका के अपने मित्र देशों से संबंध भी खराब हो रहे हैं। इतना ही नहीं अमरीका के विभिन्न विभाग भी अमरीकी सरकार की 'नियंत्रक नीति' के संबंध में विरोधी मत रखते हैं। भारत की सुरक्षा संबंधी उच्च तकनीक के निर्यात के मामले में तो ये मतभेद खुलकर सामने आ गये हैं।

भारत से भय : अमरीका का विदेश विभाग भारत को उच्च-तकनीक की बिक्री करने का इच्छुक है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके द्वारा ही उस क्षेत्र में 'सोवियत प्रभाव' को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर अमरीका के सुरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागान की मान्यता है कि भारत के सुरक्षा उत्पादक संस्थानों की सुरक्षा-व्यवस्था बड़ी कमजोर है, अतः भारत को बेची गयी हर उच्च-तकनीक रूसी हाथों में सहजता से पहुंच सकती है। पेंटागान हर मामले को केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए वह सदैव भारत को उच्च-तकनीक के बेचे जाने का विरोध करता रहा है। यही वजह है कि जब भारत ने पहले सुपरकंप्यूटर खरीदने की पेशकश की, तो पेंटागान ने इस सौदे को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह दलील दी गयी कि भारत 'कोकोम' की 'ग्रे सूची' में शामिल है। इस सूची में उन देशों के नाम शामिल हैं, जिनके बारे में संदेह किया जाता है कि ये देश अवैध रूप से अमरीका से प्राप्त तकनीक सोवियत रूस तक पहुंचा देते हैं।

१९८५ में राजीव गांधी की अमरीका-यात्रा के दौरान 'सुपर कंप्यूटर' का मामला एक बार फिर उठा। उपराष्ट्रपति जार्ज बुश ने घोषणा की थी

यह वास्तविकता है कि अमरीका भारत को जो उपकरण व उच्च तकनीक बेच रहा है, वे संवेदनशील नहीं हैं और यह भी स्पष्ट है कि ऐसे हर प्रस्ताव पर अमरीकी-पाक और अमरीकी-चीन संबंधों को दिमाग में रखकर ही वह फैसले करता है। अमरीका की मान्यता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत से अधिक पाक और चीन उसके हितों के अनुकूल हैं। इसलिए वह भारत से कोई ऐसा सौदा कभी नहीं करना चाहेगा, जिससे पाक और चीन से अमरीकी संबंधों को थोड़ी-सी भी आंच आती हो।

मनोहर कहानियाँ

अतिरिक्तांक **दीपावली** विशेषांक

प्रमुख आकर्षण

नताशा

एक ऐसे परिवार की लड़की की
रोमांचक सत्यकथा,
जहां जायदाद के बंटवारे के भय से
लड़कियों को न केवल कुंवारी
रखा जाता था अपितु उन्हें मरने के लिए
विवश भी किया जाता था

दक्षा की उत्पीड़न कथा

एक ऐसी नारी की हृदय-विदारक व्यथा-कथा,
जिस पर ससुराल में
केवल इसलिए सितम ढाया गया
कि उसका बेरोजगार पिता
दहेज की पूरी रकम देने में असमर्थ था

बिहार का निराला वर मेला

मिथिला के गौरव और मैथिलियों की
निरालीं परम्पराओं से जुड़े सौराठ मेले की
रोचक कहानी

खुशियां फिर लौट आयीं

संयम और सहनशीलता की अग्नि-परीक्षा में
खरी उतरने वाली एक ऐसी नारी की मार्मिक
कहानी, जिसका पति अपनी मां के संबंध में
गलतफहमी के कारण औरतों पर
अविश्वास करने लगा था

१५ सितम्बर तक प्रकाश्य

मूल्य-५.००

कि कुछ शर्तों पर भारत को यह कंप्यूटर बेचा जा सकता है। तब पेंटागन 'सुपर कंप्यूटर' बेचने पर तो सहमत हो गया, लेकिन वह भारत द्वारा मांगे गये 'सुपर कंप्यूटर' से कम क्षमतावाला 'सुपर कंप्यूटर' बेचने को राजी था। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि भारत को इससे अधिक विकसित उपकरण बेचने की कोशिश हुई, तो सुरक्षा विभाग द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा सकता है।

सुपर कंप्यूटर के सौदे के मामले में अमरीका के विदेश विभाग का सुझाव था कि सौदा होने के पहले भारत और अमरीका 'सुरक्षा-व्यवस्था' के मामले में सुनिश्चित हो लें, उसके बाद तय हो कि भारत किस स्तर का 'सुपर कंप्यूटर' चाहता है। लेकिन इस संबंध में समझौता हो जाने के बावजूद पेंटागान इस जिद्द पर अड़ा हुआ है कि भारत को अपेक्षित क्रे-सुपर कंप्यूटर न बेचा जाये। भारत को सुरक्षा संबंधी अन्य उपकरणों एवं अन्य तकनीक की बिक्री के संबंध में भी पेंटागाना ने वैसा ही कड़ा रुख अपनाया है। अमरीका की युद्धक-विमान निर्माता कंपनी 'नार्थ-रोप कार्पोरेशन' भारत को एफ-२० टाइगर शार्क लड़ाकू विमान बेचना चाहती थी। इस विमान के संबंध में भारतीय अधिकारियों को जानकारी देने के लिए अमरीकी सुरक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करने में इस कम्पनी को तीन साल लग गये। इसी प्रकार 'इंटरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ' (आईटीटी) कंपनी 'भारत इलेक्ट्रानिक' को रात्रि में देखने में सक्षम एक उपकरण बेचना चाहता था, जिसकी सुरक्षा-विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने में उसे दो वर्ष से अधिक का समय लग गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी सेना को जैसे ही यह पता चला कि आईटीटी यह उपकरण भारत को बेचना चाहता है, तो इसे उसने 'प्रतिबंधित उपकरणों' की सूची में दर्ज कर लिया।

भारत को संवेदनशील उच्च तकनीक की बिक्री के विरोध में पेंटागान के अधिकारी एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार भारत के दौरे पर गया एक अमरीकी बड़ी सरलता से उस स्थान पर प्रवेश कर गया था, जहां मिग युद्धक विमान के किसी उपकरण का परीक्षण हो रहा था। भारतीय अधिकारी इस आधार पर 'तकनीक-चोरी' के अमरीकी भय को बेबुनियाद बताते हैं कि यहां रूसी और पश्चिमी सुरक्षा उत्पादन संस्थानों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। १९८४ में भारत तकनीकी जानकारियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर सहमत भी हो गया था। बहरहाल, अमरीका इस संबंध में पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ है। वह यह तो मानता है कि भारत जानबूझकर रूस को कोई तकनीकी जानकारी नहीं देगा, लेकिन इसके साथ ही वह यह भी विश्वास करता है कि रूस बड़ी सरलता से भारत में 'औद्योगिक गुप्तचरी' कर सकता है।

यही भय है, जिसकी वजह से पेंटागन ने यह नीति बना ली है कि भारत को वही तकनीकी जानकारी बेची जाये जो सोवियत रूस के पास पहले से मौजूद हो या जिसे स्वयमेव विकसित कर लेना रूस के लिए कोई बड़ी बात न हो। मसलन जीइ-एफ-४०४ इंजन—भारत के हलके लड़ाकू विमानों में काम आनेवाला यह इंजन अमरीका ने भारत के साथ-साथ आधे दर्जन से अधिक अन्य मुल्कों को भी बेचा है। युगोस्लाविया इस इंजन का नया ग्राहक है। अमरीका इस इंजन का संयंत्र चीन को भी बेचना चाहता है। यदि यह इंजन कम्युनिस्ट देशों को भी बेचा जा रहा है, तो निश्चित है कि इसे 'संवेदनशील तकनीक' नहीं कहा जा सकता।

अतः यह वास्तविकता है कि अमरीका भारत को जो उपकरण व उच्च तकनीक बेच रहा है, वे संवेदनशील नहीं हैं और यह भी स्पष्ट है कि ऐसे हर प्रस्ताव पर अमरीकी-पाक और अमरीकी-चीन संबंधों को दिमाग में रखकर ही वह फैसले करता है। अमरीका की मान्यता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत से अधिक पाक और चीन उसके हितों के अनुकूल हैं। इसलिए वह भारत से कोई ऐसा सौदा कभी नहीं करना चाहेगा, जिससे पाक और चीन से अमरीकी संबंधों को थोड़ी सी भी आंच आती हो। अतः अमरीका भारत को जो उच्च तकनीक देगा, वह पाक और चीन को भी सुलभ होगी। भारत के लड़ाकू विमानों में जो जीइ-एफ-४०४ इंजन लगा है, वह पाकिस्तान के एफ-६ युद्धक विमान में भी लगा है और चीन को भी यह इंजन मिल जायेगा। अमरीका की इस नीति से सहज ही समझ लेना चाहिए कि भारत को अमरीका से कोई अतिविशिष्ट तकनीकी जानकारी नहीं मिल सकती।

—अनिल गुप्ता

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर

प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की सुरक्षा
के नाम पर उनके आवास की
जो अभूतपूर्व किलेबंदी की गयी है,
वह राजधानी के आम लोगों की
जिंदगी और उनके दर्शनार्थ आनेवाले
लोगों के लिए कौन-सी लाइलाज
परेशानी पैदा कर रही है ? इस
किलेबंदी से आम आदमी के मन
में राजीव की कैसी
छवि उभर रही है ?

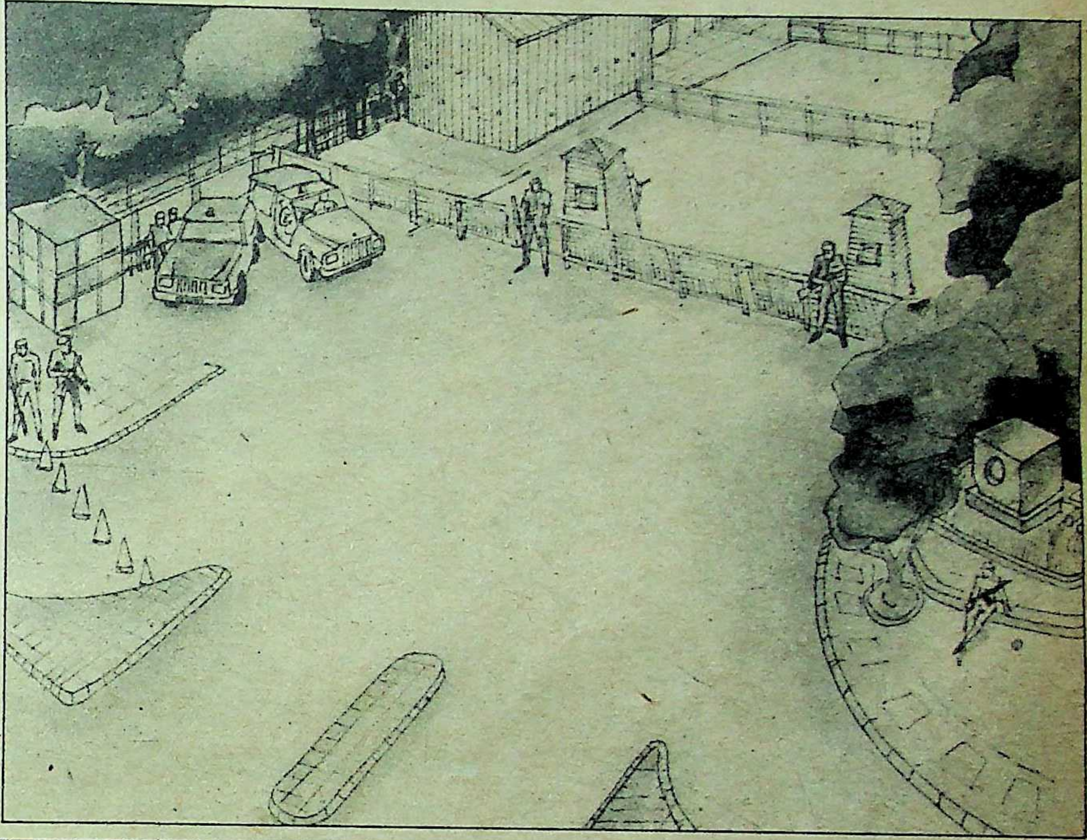

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आवास ७, रेसकोर्स रोड से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर १० जुलाई को घटित एक प्रसंग पर गौर करना उनके भविष्य के लिए इस समय कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बड़ा शोर है कि वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद और वी०सी० शुक्ला राजीव गांधी की सरकार को अस्थिर करने की गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन उक्त प्रसंग इन सबकी सम्मिलित कार्यवाहियों से भी अधिक अहमियत रखता है। इस प्रसंग से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की दुर्जेय सुरक्षा व्यवस्था से (भले ही यह कितनी ही जरूरी क्यों न हो) लोगों के मन में स्थायी रूप से यह बात घर कर गयी है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। इस प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत के प्रति लोगों में कितनी अश्रद्धा पैदा हो रही है।

सुरक्षा का मजाक : सफदरजंग और रेसकोर्स के दोराहे की ओर अधेड़ अवस्था का एक गढ़वाली चहलकदमी करता हुआ जा रहा था। उसके कंधे पर एक झोला लटका था। वाहनों का आना-जाना उस समय बंद था, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से गुजरनेवाले थे (जबकि किसी को सही समय और सही रूट की जानकारी नहीं थी)। कुछ लोग पैदल आ-जा रहे थे, लेकिन इन लोगों से कहीं अधिक संख्या वहां तैनात पुलिस के स्टेनगनधारी जवानों की थी, जो हर आने-जाने वाले पर खोजी निगाह जमाये हुए थे, इनमें से एक जवान को उस गढ़वाली पर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वह बार-बार अपने कंधे पर लटके झोले को छू रहा था। उसने गढ़वाली

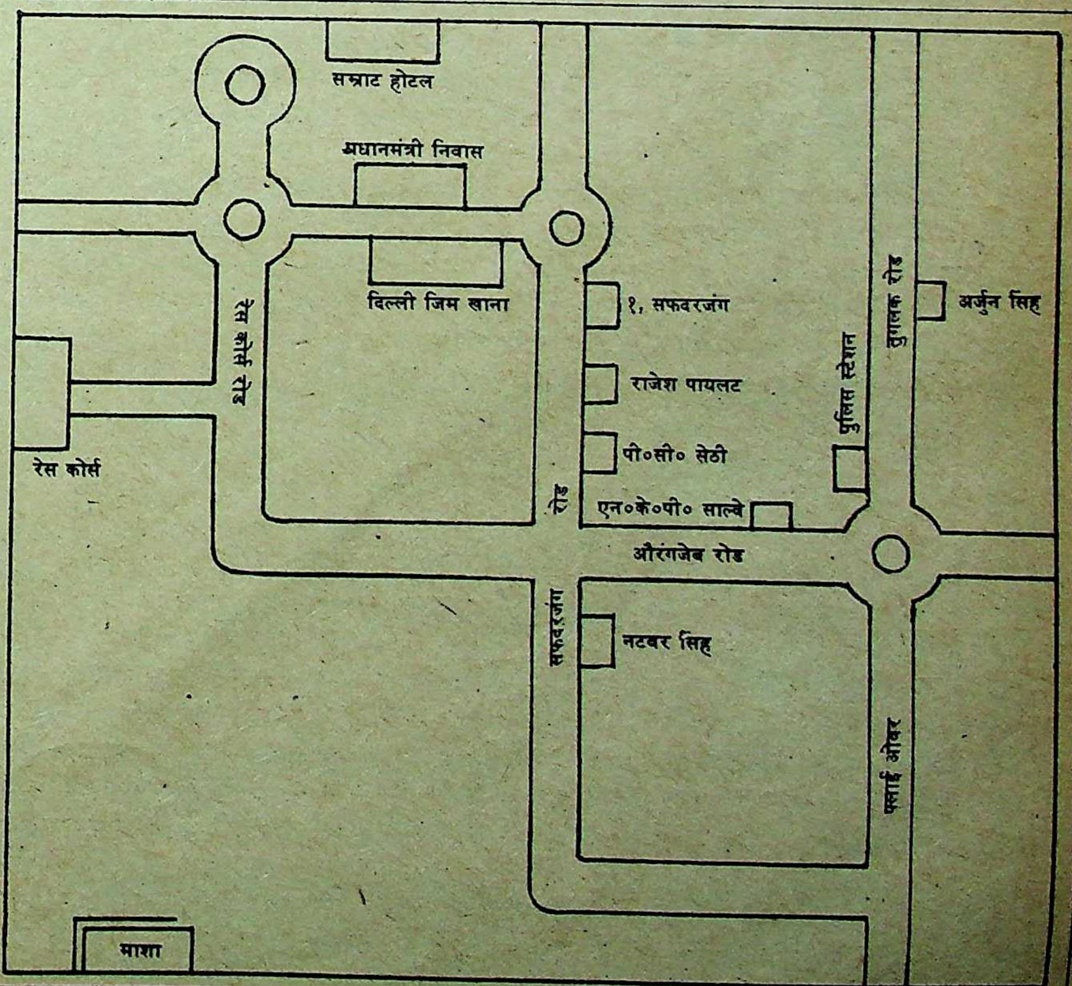
सम्राट होटल
प्रधानमंत्री निवास
दिल्ली जिम खाना
रेस कोर्स रोड
रेस कोर्स
१, सफदरजंग
राजेश पायलट
पी०सी० सेठी
एन०के०पी० साल्वे
पुलिस स्टेशन
तुगलक रोड
अर्जुन सिह
औरंगजेब रोड
सफदरजंग रोड
नटवर सिह
फ्लाई ओवर
माशा

सत्यकथा

सितम्बर अंक
मूल्य ५:००

विशेष आकर्षण

अलताफ की प्रेम कथा

एक दौलतमंद से शादी के बावजूद आइशा द्वारा अंतिम सांस तक अपने प्रेमी अलताफ को न भुला पाने की एक अजीबोगरीब कथा

आबरू बेगम

शेरशाह सूरी के खिलाफ बगावत करनेवाली मुगलिया खानदान की शहजादी आबरू बेगम की हिम्मत, दिलेरी और खूबसूरती में वलीअहद के कैद हो जाने की इतिहास-कथा

मेजर पत्नी दुर्गेश्वरी की हत्या का रहस्य

नेपाल के एक मेजर की पत्नी श्रीमती दुर्गेश्वरी पांडेय की बहराइच सीमांत पर लूटपाट करनेवाले बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने की सनसनीखेज कथा

क्या वे टोनही थीं ?

म०प्र० के रायपुर क्षेत्र के एक गांव में एक बैगा द्वारा जादू-टोने की आड़ में महिलाओं के साथ अत्याचार किये जाने की कथा

तथा और भी

० प्रेम-अपराध ० नारी-अपराध ० रहस्य-रोमांच की अछूती सत्यकथाएं—नए रूप, एवं साज-सज्जा के साथ

से पूछा, "इसमें (झोले में) क्या है?" गढ़वाली ने कुटिलतापूर्वक उलटे सवाल किया, "अगर मैं कहूं कि इसमें सइफल है, तो आप क्या करेंगे?" यह सुनकर पुलिस का जवान दहाड़ा, "मजाक करता है, उठाकर बंद कर दूंगा।" इस पर "अरे! देख लो इसमें क्या है?" कहते हुए गढ़वाली ने अपना झोला कंधे से उतार लिया। इससे पहले कि वह गढ़वाली स्वयं अपना झोला दिखाता, उस सुरक्षा जवान ने झोले में हाथ डाल दिया। तब तक वहां पैदल चलनेवाले कुछ और लोग जमा हो गये थे। सुरक्षा जवान ने जब झोले से हाथ बाहर निकाला, तो उसके हाथ में कोल्ड ब्रांड का सरसों के तेल का एक केन था। जिसे देखकर आसपास उपस्थित लोगों के चेहरों पर मुस्कराहट खेल गयी। वह गढ़वाली समझाता रहा कि इस केन में ढक्कन नहीं है। कहीं तेल बाहर गिर तो नहीं रहा है, यही देखने के लिए ही, वह झोले को बार-बार छू रहा था। तभी मारुति जिप्सी जीप में बैठे एक सिख पुलिस अधिकारी ने उस पुलिस के जवान से उस गढ़वाली को अपने पास लाने के लिए कहा। इस बीच वह गढ़वाली बोल उठा, "लो आतंकवादी बुला रहा है।" पता नहीं फिर क्या हुआ, उस गढ़वाली को जिप्सी जीप में बिठाकर वे लोग सम्राट होटल की तरफ चले गये।

यह एक अतिरंजित प्रसंग हो सकता है, लेकिन इस इलाके में प्रतिदिन थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद लंबे समय तक चलनेवाली इस नाकेबंदी ने दफ्तर आने-जानेवाले लोगों के लिए ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिनका अंत होता नजर नहीं आता। उस दिन तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और औरंगजेब रोड को भी बंद कर दिया गया था। ये वे इलाके हैं, जहां बहुत थोड़े मंत्री रहते हैं, लेकिन उनके चुनाव-क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने आते हैं।

बिगड़ता माहौल : एक प्रसंग नेहरू स्मारक भवन के तीन मूर्ति दरवाजे का भी है। तपती धूप में सड़क खुलने की प्रतीक्षा करता एक स्कूटर सवार अपने साथी से यह कहता हुआ सुना गया, "आपने उन्हें वोट दिया, उसके बाद यही कुछ तो होना है कि हम तो धूप में तपते रहें और वे वातानुकूलित कारों में घूमते हुए हमसे लुका-छिपी का खेल खेलते रहें।" ऐसी नाकेबंदी से सर्वाधिक पीड़ित होते हैं, बस यात्री और ये ही वे लोग हैं जो राजीव सरकार की धाराप्रवाह कटु आलोचना करते हैं। इनमें से कुछ लोग यह तो समझ सकते हैं कि यह खतरनाक समय है और कुछ तकलीफ उठा लेनी चाहिए, लेकिन उनकी मान्यता है कि कोई-न-कोई ऐसे उपाय जरूर किये जाने चाहिए, जिससे लोगों की तकलीफें कुछ कम हो सकें। एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए किया जा रहा यह बंदोबस्त आम आदमी के लिए तकलीफदेह होता जा रहा है, लेकिन उस अधिकारी की मान्यता है कि प्रधानमंत्री की छवि को वे तकलीफें ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिनका सामना राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य प्रार्थियों को उनसे मिलने की कोशिशों में करना पड़ता है।

मुलाकात में दिक्कतें : ७, रेसकोर्स के स्वागत कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए मुख्य अवरोधक (बैरियर) को पार करके काफी दूर तक भीतर जाना होता है। इस बैरियर पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। उनके लिए यह संभव ही नहीं है कि वे आनेवाले हर व्यक्ति को पहचानते हों। इस कारण वे किसी को भीतर जाने की अनुमति देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। जो भी वहां पहुंचता है, वह यही दावा करता है कि उसने एम०एल० फोतेदार, सतीश शर्मा, वी० जार्ज या स्वयं प्रधानमंत्री से मिलने की पूर्व अनुमति ले रखी है। सुरक्षाकर्मियों की सहायता के लिए वहां कोई राजनीतिक सहायक नियुक्त नहीं है।

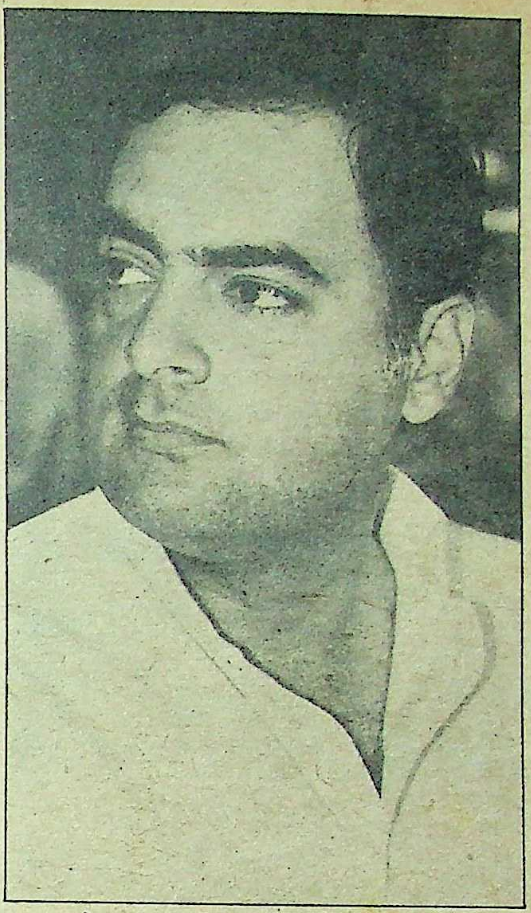
सुरक्षा के नाम पर बदनामी : राजीव गांधी

आमतौर पर होता यह है कि जब कोई व्यक्ति सुरक्षा-अधिकारियों को (मिलने की) पूर्व अनुमति प्राप्त होने का विश्वास दिला देता है, तब टेलीफोन के जरिये इसकी पुष्टि की जाती है। उसके बाद एक सुरक्षाकर्मी उसे स्वागत कक्ष की ओर ले जाता है। आगंतुक की परेशानियां अभी दूर नहीं होतीं—स्वागत कक्ष तक पहुंचने के बाद भी उसे घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मसलन, यदि उसने सप्ताहों पूर्व जार्ज से मिलने का समय लिया है, तो हो सकता है कि वहां पहुंचकर उसे पता चले कि जार्ज या तो प्रधानमंत्री के साथ हैं या शहर से बाहर हैं। इसका मतलब है कि जार्ज से मिलने के लिए उसने लंबी प्रतीक्षा, कड़ी पूछताछ आदि की जो जहमत उठायी थी, वह सब बेकार चली गयी। अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जिला पार्टी के पदाधिकारियों को भी ऐसे अनुभव होते हैं और अपनी खीज मिटाने के लिए वे इन लोगों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए चले जाते हैं, फिर कभी लौटकर नहीं आते। इस प्रकार राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था उनकी अपनी ही पार्टी के असरदार कार्यकर्ताओं को नाराज करने का कारण बन गयी है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना था, "हमने १९८५ में ही सुझाव दिया था कि राजीव गांधी से लोगों को मिलवाने में वही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में अपनायी जाती थी, लेकिन इस सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।" यह प्रक्रिया बड़ी सीधी और सरल थी। श्रीमती गांधी से यदि एक व्यक्ति मिलना चाहता था, तो वह स्वयं और यदि बहुत से लोग समूह में मिलना चाहते थे, तो उनका मुखिया निर्धारित तिथि से कम-से-कम एक दिन पूर्व मिलनेवालों के नाम-पते एवं आवश्यक जानकारियां संबंधित अधिकारी को दे देता था। फिर अगले दिन प्रातः वे सभी लोग प्रधानमंत्री निवास पहुंचते थे, मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद स्वागत कक्ष के काउंटर पर उनसे कुछ पूछताछ होती थी, उसके बाद उन्हें श्रीमती गांधी के पास एक कक्ष में पहुंचा दिया जाता था।

एक गुप्तचर अधिकारी ने दावा किया कि ऐसी मुलाकातों में कभी कोई हादसा नहीं हुआ। वह मारी गयीं, तो उन्हीं लोगों द्वारा, जिन पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी।

हरियाणा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश के एक सांसद ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात की थी। इन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री से यह उनकी पहली मुलाकात है और यह मुलाकात भी वहां उपस्थित संसदीय दल के एक पदाधिकारी की मदद से संभव हो सकी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हाल में जो नये उपाय किये गये हैं, उनके अतर्गत प्रतिष्ठित जिमखाना क्लब के सदस्यों के लिए एक विशेष कार्ड रखना अनिवार्य बना दिया गया है, क्योंकि यह क्लब प्रधानमंत्री निवास के ठीक पीछे मौजूद है, लेकिन ऐसे नियमों से लोग खिन्न हो जाते हैं।

एक अनुभवी और पुराने सुरक्षा सलाहकार के अनुसार हमें इजरायल में अपनायी जा रही सुरक्षा-व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। इजरायल उन देशों में से है, जहां आतंकवाद का सर्वाधिक खतरा मौजूद है, लेकिन उनकी सुरक्षा-व्यवस्था ऐसी है जो दिखायी नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति हर कहीं महसूस की जा सकती है। ऐसी ही व्यवस्था भारत में भी करनी चाहिए। लेकिन यहां हो यह रहा है कि सड़क के बीचोबीच एक अंबेसडर कार खड़ी करके सड़क बंद कर दी जाती है, यह अनावश्यक दिखावा है। इससे बेहतर तो पुरानी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत पुलिस के सशस्त्र जवान पूरे रूट को ही बंद कर देते थे।

एक अपराध विशेषज्ञ का सुझाव है, "गुप्तचर व्यवस्था तो पुख्ता हो, लेकिन उसका दिखावा कम-से-कम हो।" आज राजीव गांधी को व्यक्ति-व्यक्ति से अधिकतम निकट का संपर्क बनाकर रखना जरूरी है, लेकिन क्या कोई उक्त सुझावों की ओर ध्यान देगा? एक पुलिस अधिकारी ने उत्तेजित होकर कहा, "यह सोचना राजीव गांधी का काम है।" वह अधिकारी शायद ठीक कह रहा था। बचने के लिए व्यक्ति जितना छुपता है, आफतों का शिकंजा और कसता चला जाता है।

—विशेष प्रतिनिधि

अमजद अली खां

सरोद और जिंदगी की जुगलबंदी का दूसरा नाम

आकर्षक व्यक्तित्व,
सौम्य स्वभाव और संगीत के प्रति
समर्पित उस्ताद अमजद अली खां
ने सरोद वादन के क्षेत्र में
अव्दितीय ख्याति अर्जित की है।
प्रस्तुत है इस महान
कलाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व
का एक आकलन :

इसी साल जून महीने में पेरिस में उस्ताद अमजद अली खां का एक कार्यक्रम था। सरोद को आकाश की ऊंचाई तक ले जाकर और समुद्र में गोता खिलाकर अमजद अली जब ग्रीन रूम में आराम कर रहे थे, तब कुछ भारतीय उनसे मिलने पहुंचे। एक उम्रदराज सज्जन, जिन्होंने वर्षों से भारत का मुंह नहीं देखा था, अपनी आंखों में एक परत आंसू छिपाते हुए खड़े थे।

"बेटा!" उन सज्जन ने कहा—"मैंने तुम्हें १९५६ में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के सामने ग्वालियर के जयविलास पैलेस में सरोद बजाते सुना था। तब भी मैं झूम गया था और आज भी झूम गया। भगवान तुमको लंबी उमर दे।"

अमजद अली बड़ी कृतज्ञता से भरकर यह किस्सा सुनाते हैं और उनकी रोमांचित आंखों में उस समय शायद ग्वालियर के जीवाजीगंज मोहल्ले का एक हवेलीनुमल मकान तैर जाता है, जहां उनका बचपन गुजरा था।

मकान क्या एक छोटी-मोटी धर्मशाला है—उस्ताद हाफिज अली खां की हवेली। हालांकि नगर निगम के बादामी पड़ चुके रजिस्टर में मालिक का नाम अमजद अली खां पुत्र मरहूम हाफिज अली खां साकिन ग़्वालियर लिखा है। लेकिन इस हवेली ने सरोद की आहटें कई सालों से नहीं सुनीं। पिछवाड़े मस्जिद से आनेवाला अजान का स्वर ही हवेली का निकटतम संगीत है।

अपने बचपन के घर की याद अमजद अली बड़े सोच में पड़ कर करते हैं। उनकी मोम की तरह मुलायम आवाज जैसे अतीत की बावड़ी में डूब जाती है—"अब्बा हमारे बड़े दिलचस्प आदमी थे। म्यूजिक के अलावा और किसी चीज से उन्हें गरज रही हो, इसकी याद नहीं पड़ती। हवेली की छत पर दालान के सामने वाले बड़े कमरे में वह बैठे रहते थे। वहां का रास्ता सीधे बरामदे से जाता था। सब मिलने वाले नहीं पहुंचते। हाल यह होता था कि कोई शादी का न्योता देने आया है, तो उस्तादजी उससे बगैर पानी पूछे एक राग, एक रागनी गाते और एक टुकड़ा सुनाये जा रहे हैं। आनेवाला पहलू बदल रहा है, बैठ रहा है। तब कहीं जाकर उस्तादजी को याद आता है कि आया है तो कोई काम होगा।"

अमजद अली के लिए पिता से रिश्ता दो धारी तलवार का था—"बचपन तो मैंने देखा ही नहीं। बच्चे कंचे खेलते थे, गिल्ली-डंडा खेलते थे, पहिया चलाते थे, पतंग उड़ाते थे और हम सरोद लेकर सा रे गा म प निकालते रहते थे। और उस जमाने में तो हम तबला भी बजाते थे और गाते भी थे।"

उस जमाने में, जब अमजद अली उस्ताद नहीं हुए थे—उनके एक दोस्त होते थे माधव उमेड़कर। माधव शास्त्रीय गायक हैं और अमजद प्यार से उन्हें राजू कहते है। उमेड़कर बाकायदा उमड़कर अमजद की याद करते हैं—"आप जानिए कि हसीन तो थे ही हमारे अमजद भैया और हाथ में मिठास बहुत थी। हवेली की एक कोठरी में बैठकर वे रियाज करते थे, मैं सुनता था। जब मैं रियाज करता तो वे सुनते थे। घर के बगल से सुवर्ण रेखा नदी बहती थी (जो अब नाला बन कर रह गयी है)।"

हाफिज अली खां साहब के पुरखे अफगानिस्तान से ग्वालियर दरबार में आये थे। दौलतराम सिंधिया के जमाने में। हाफिज अली ने हमारे रेलमंत्री माधवराव सिंधिया के इसी नाम वाले दादाजी और फिर इनके पिताजी जीवाजी राव सिंधिया का जमाना देखा। पर १९४५ में जब अमजद का जन्म हुआ, हाफिज अली का मन दरबार से उखड़ चुका था। अगले दस-ग्यारह साल इसी उखड़ेपन से उन्होंने दरबार में काट दिये। अमजद याद करते हैं—'! मुझे दरबारी सलीका सिखाने दरबार में ले जाया जाता था। कोई मुअज्जिम मेहमान आता, तो उसके लिए मैं भी कभी-कभी सरोद बजाता। लेकिन तब तक कल्चर बदल रही थी और शास्त्रीय कलारत्नों के बगैर भी काम चलने लगा था। सो हमारे अब्बाजान को यहीं ठीक लगा कि दिल्ली जाकर बसा जाये। श्रीराम भारतीय कला केन्द्र से न्योता भी था।"

तो, दो बेटियों और तीन बेटों को लेकर उस्ताद हाफिज अली खां ने ग्वालियर की हवेली रिश्तेदारों के हवाले की और झोला-डंडा समेटकर आ गये दिल्ली। आज जहां कमानी आडीटोरियम और श्रीराम भारतीय कला केन्द्र है, वहां बैरकनुमा मकानों में ये लोग रहते थे और उन्हीं में से कुछ बैरकों में कला का केन्द्र भी चला करता था। उन दिनों अमजद अली ने बड़े-बड़े उस्ताद गवैयों को देखा-सुना और अपनी तालीम भी मांजते रहे।

वे बड़े मजेदार दिन थे। अमजद अली बहावलपुर हाउस (जहां अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है) होते हुए बंगाली मार्केट पहुंचते। वहां से रिफ्यूजी मार्केट और फिर मार्डन स्कूल के पीछे दरवाजे से होते हुए अंदर स्कूल में।

स्कूल में बाकी तो सब ठीक था, पर अमजद अली को खेल का घंटा बड़ा नागवार गुजरता था, "यों करने को तो हमने घुड़सवारी भी की और दौड़ भी लगायी, पर दिमाग तो संगीत में ही लगा रहता था। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा कि हमारी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो अब गाने-बजाने दीजिए। पहले तो उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा, लेकिन फिर वह भी मान ही गये। इसके बाद तो सब खेलते थे और मैं सरोद बजाता रहता था। बाद में तो कालेज के वार्षिकोत्सवों में भी खूब बजाया।"

खाली वक्त में अमजद अली नाथू स्वीट्स चले जाते थे या बंगाली स्वीट्स। आज के मुकाबले सस्ते का जमाना था और खूब मजे में खाया-पिया जा

सकता था। इसके बाद साइकिल लहराते हुए घर। आज भी अमजद अली का कार्यक्रम दिल्ली में होता है, तो नाथू स्वीट्स पर उसका इश्तहार जरूर लगता है।

स्कूल भी निपट गया। कालेज जाने की जरूरत अमजद अली ने समझी नहीं। उनके एक बड़े भैया कालेज में संगीत की तालीम पा रहे थे। आज वह ग्वालियर के म्यूजिक कालेज में पढ़ाते हैं। दूसरे, रहमत अली सरोद में ध्रुपद परंपरा के माने हुए कलाकार हैं और आकाशवाणी में प्रोड्यूसर भी। रहे अमजद, तो हाथ में सरोद था और नापने के लिए दुनिया पड़ी थी।

"तो साहब हमने कानसर्ट में जाना शुरू किया। पहले तो लोग देखें और कहें कि यह लड़का क्या बजाएगा। पर जब थोड़ा बजा चुके, तो फिर वे सांस थामकर बैठे रहे। शुरुआत में पैसे ज्यादा नहीं मिलते थे, तो सारा सफर थर्ड क्लास में होता था। सस्ते होटल में ठहरते थे। सस्ता खाते थे। यह खयाल रखते थे कि मान लो आयोजक पैसे न दें, तो चल जाये। (आज तो अमजद खुद भी बड़े आयोजकों में से हैं और साल में कम-से-कम चार बड़े समारोह कराते ही हैं।) थर्ड क्लास में साज-बाज लेकर जाना खासी दिक्कत का काम होता था। कोई संगीत को जानने-चाहने वाला आदमी मिल गया, तो ठीक और अगर कोई बेसुरा मिल गया, तो गये काम से। फिर जैसे-जैसे पैसा मिलने लगा, हमारी सफरी हैसियत बढ़ने लगी।"

पन्द्रह साल की उम्र में अमजद अली जिसे अंग्रेजी में इस्टेबिलश होना कहते हैं— हो चुके थे। इसी साल यानी १९६० में उन्हें प्रयाग संगीत समिति ने 'सरोद सम्राट' की उपाधि दे दी थी। इसके १५ साल बाद, १९७५ में इन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली। उस समय तक कलाओं के क्षेत्र में यह उपाधि पाने वाले अमजद अली सबसे कम उम्र के कलाकार थे। और हां, तब तक वह उस्ताद भी हो चुके थे।

उस्ताद का खिताब : पहले के वक्तों में उस्ताद का खिताब बाकायदा एक जलसा करके लायड और काबिल कलाकारों को दिया जाता था। इसका एक मतलब यह होता था कि अब यह कलाकार लोगों को सिखाने लायक हो गया। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्रों में इस बात को लेकर काफी भृकुटियां तनी हुई हैं कि अमजद अली खां ने अपने आपको उस्ताद घोषित कर दिया और उन्हें यह खिताब किसी ने दिया नहीं। अमजद अली पहले इस तरह की बहस में फटाक से कूद पड़ते थे। अब आदत बदल गयी है। फिर भी कहते हैं, "लोगों ने अपने आप नाम के आगे उस्ताद लगाना शुरू कर दिया। अनाउंसमेंट में बोलने लगे, परिचय में लिखने लगे। फिर अखबारों में छप गया। अब अगर किसी को लगता है कि हम उस्ताद होने लायक नहीं हैं, तो पांव छू कर तो किसी से मनवाने जाते नहीं।" यह अमजद अली की अदा है कि कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। उनके इस पराक्रम का मजा पहले भी कई बार लोग चखते रहे हैं और अब भी चलते-फिरते वह अपनी जिद को उजागर करते रहते हैं।

कोई पांच साल पहले अमजद अली कला के अखाड़े के सबसे बड़े पहलवान अशोक वाजपेयी से जूझ गये थे। मसला था कि साहब म०प्र० में केवल अलाउद्दीन खां साहब की याद में अकादमी क्यों बनेगी? इसलिए कि वह रविशंकर के ससुर हैं? काफी दिनों शब्दभेदी वाण चलते रहे और अमजद ने एक बार यह भी घोषणा कर दी कि वह म०प्र० सरकार के कार्यक्रम करेंगे ही नहीं। बाद में थोड़ा-बहुत खींचतान हुई और उन्होंने म०प्र० के कलाप्रशंसकों को माफ कर दिया।

इसी विवाद में रविशंकर से उनके झगड़े का बीज छिपा हुआ है। १९८३ में अमजद अली ने अखबारों को दनादन इंटरव्यू देने शुरू कर दिये कि रविशंकर कला में राजनीति करते हैं। कुछ ही दिन पहले रविशंकर की आत्मकथा बाजार में आयी थी। उस पर भी अमजद अली का नजला पड़ा, "जिसको मन में आया ग्रेट कह दिया, जिसकी चाहा बेइज्जती कर दी।" रविशंकर ने जवाबी इंटरव्यू दिये और मसला तूफान हो गया। फिर अचानक एक दिन सबने सुना कि दोनों महान कलाकारों में मेल हो गया है।

संवेदनशील इतने कि नाक पर मक्खी न बैठने दें। हवाई जहाज से दिल्ली लौट रहे थे कि टर्मिनल में लाउडस्पीकर पर बजते हुए सरोद पर उनका ध्यान गया। उनका ही बजाया हुआ कोई राग बज रहा था, पर संगीत व्यवस्था पर आवाज कुछ ऐसी आ रही थी जैसे कोई सरोद की गर्दन ऐंठ रहा हो। बहुत बेचैन अमजद अली शिकायत काउंटर पर पहुंचे, शिकायत दर्ज करवाई कि अपना सिस्टम सुधारिए। लेकिन इंडियन एयरलाइंस वालों ने अपना सिस्टम सुधारने की तो छोड़िए, आज तक जवाब तक नहीं दिया।

शादी : शादी का भी मजेदार किस्सा है। नमकीन सूरत और हुनर पर मरने वालियों की कमी नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि उनमें से कोई पसंद न आयी हो। "कई तो बड़े घर की थीं और उनमें से कुछ ने तो साथ आकर रहना शुरू कर दिया। अब मैं थोड़ा छोटे शहर में पला हुआ आदमी—मेरे दिमाग में तो औरत के नाम पर घर गृहस्थी ही आती है। अब आलम ये कि मैं उनसे कहूं कि भई शादी-वादी होनी चाहिए और वे कहें कि नहीं वैसे ही साथ रहते हैं। तो ये वैसे ही वाला चक्कर नहीं जमा और सबका साथ छूट गया।"

सरोद सम्राट : अमजद अली खां

-इनमें से किसी का नाम बताने में अमजद अली खां शरमा जाते हैं—"छोड़िए! जो दफन है, उसे रहने दीजिए। अब तो मैं हूं, मेरी जिंदगी है, सरोद है, शुभलक्ष्मी है और बेटे हैं, अमान और अयान।" शुभलक्ष्मी भी अमजद की जिंदगी में सुबह के सपने की तरह आयीं। सफलता मिल चुकी थी, पैसा मिल रहा था और ख्याति समुद्र को कब की पार कर चुकी थी। लेकिन अपना अकेलापन दूर नहीं हो रहा था।

"फिर एक पार्टी में वे मिलीं", अमजद अली कहते हैं। उनकी आंखों में वह लम्हा याद करते वक्त सितारे जगमगाते हैं—"बहुत नफीस, रिजर्व और सुंदर-सी लड़की। मुझे पता था कि वे डांसर भी हैं। असमिया मूल की शुभलक्ष्मी भरतनाट्यम की नामी नृत्यांगना रह चुकी हैं। और रुक्मणी देवी अरुंडेल की शिष्या हैं। पहली बार मिलने पर ही मुझे कुछ ऐसा हुआ, जैसा पहले कभी हुआ नहीं था। फिर हम मिले और कई मुलाकातों के बाद शादी का फैसला कर लिया"

शादी भी कोई ऐसे ही नहीं हुई। बड़े-बड़ों के चेहरे सामने आ गये। लोगों ने मिलना-जुलना बंद कर दिया। "हमारे घर की तरफ से भी और इनके यहां से भी। इन बुजुर्गों के लिहाज से तो शायद कयामत आ गयी थी। फिर अपना नया घर-संसार बनाया। एक-एक चीज जोड़ी।" अब अमजद अली के पास दिल्ली में सबसे अभिजात कालोनी पंचशील पार्क में अपनी कोठी है जो पिता, पूर्वजों और समकालीनों की तस्वीरों और स्मृतियों से भरी हुई है। निचली मंजिल पर शुभलक्ष्मीजी का राज चलता है और ऊपर अमजद अली का।

"यहां रहकर मैं बहुत असामाजिक हो गया हूं। दुनिया-जहान छोड़ें, पड़ोस का ही कुछ पता नहीं रहता। पहले मैं ऐसा नहीं था और आगे भी वैसा नहीं रहूंगा। मैं अपने आपको बदलने की कोशिश कर रहा हूं," अमजद कहते हैं। अमजद अली के अनुसार शुभलक्ष्मी अगर नाचती रहतीं, तो आज उनके बराबर कोई न होता। तब क्या विवाह ने उनके कलाकार का गला नहीं घोंट दिया?

"नहीं" अमजद बोलते हैं, सफाई के से स्वर में—"लेकिन, मैं जितना सोचता हूं, उससे भी बड़ी गृहस्थन वे हैं। उनको गृहस्थी के अलावा और किसी में मजा नहीं आता। वैसे हम दोनों मंच पर साथ-साथ कार्यक्रम भी कर चुके हैं, पर हमारी [illegible] जुगलबंदी तो घर में ही जमती है।"

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

—आलोक [illegible]

साक्षात्कार /अमजद अली खां

कला को सरकार से भारी खतरा है

"हमारी सरकार भारतीय शास्त्रीय कला की हिफाजत का जितना ढिंढोरा पीटती है, हकीकत में इस बारे में कोई ध्यकान नहीं दिया जाता। कलाएं जिन प्रचार माध्यमों से फलफूल सकती हैं, उनमें शीर्ष पदों पर ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनका कला से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है।"

यह कहना है प्रख्यात सरोद-वादक उस्ताद अमजद अली खां का। उनसे कला, संस्कृति व उससे जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा हुई। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश :

माया : पुराने समय में राजा-महाराजा थे तथा आज लोकतांत्रिक सरकार है। संगीत के विकास के लिए आप किस स्थिति को श्रेष्ठ मानते हैं ?

खां : राजा-महाराजाओं के जमाने में हर श्रेणी का कलाकार अपना एक स्थान पाता था। कोई भी कलाकार चाहे वह गायक हो या वादक, छोटे-छोटे रियासत के राजा द्वारा सम्मान पाता था। उनको अपने कार्यक्रम के दौरान कभी पदक, कभी हार या स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता था, जो कि किसी भी कलाकार व कला की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कलाकारों की आज की जिंदगी में ज्यादा प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां हैं। सुरक्षा की कमी है। जागरूक जनता किसी भी कलाकार को ठोंक-बजाकर देखती या सुनती है। जब वह देखती है कि इसमें दम नहीं, तो 'तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही'। यानी जनता का यही नजरिया है। सुरक्षा की दृष्टि से अपने अच्छे दौर में जो कलाकार चार पैसे बचा ले, वही काम आते हैं। वैसे आज भी कई ऐसे हैं, जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए, पर उन्हें वह नहीं मिल रहा है। कई बगैर सम्मान के ही गुजर गये।

माया : आप ने कलाकार के व्यक्तिगत प्रोत्साहन की बात कही, लेकिन कलाओं के संपूर्ण विकास के लिए, राजदरबार व लोकतांत्रिक-दरबार दोनों में से किस का होना लाभप्रद है ?

खां : राजदरबार, क्योंकि उस समय हर शहर में अपनी विरासत को कायम रखने के लिए वहां की चीजों (कलाओं) का संरक्षण किया गया। परन्तु, अब एक ही जगह सब चीजों को लेकर रखना है, उनकी प्रदर्शनी करनी है। इससे कई चीजें टूट गयीं, गिर गयीं या उनका स्वरूप ही बदल गया। संगीत के क्षेत्र में भी यही बात हुई। आकाशवाणी के ही संगीत विभाग को लीजिए। वहां जो भी कलाकार अफसर बनकर आता है, वह चूंकि एक अलग घराने से संबंधित है, इसलिए अपने घराने को छोड़ अन्य सभी घरानों के कलाकारों के संगीत को खतम कर देता है, यदि रखता भी है, तो ऐसे बेसुरे, बेताल वाले टेप में, कि वह सुनने लायक ही नहीं होता।

माया : ऐसा कोई उदाहरण आप देंगे ?

खां : नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। प्रत्येक नया आने वाला पिछले को समाप्त कर देता है।

माया : तो क्या सरकार कला का संरक्षण नहीं कर रही है ?

खां : बिलकुल नहीं, सरकारी कला-संरक्षण से तो कला की विरासत ही नहीं रहेगी। कला को सरकार से बहुत भारी खतरा है। आकाशवाणी में कई महानिदेशक ऐसे भी आते हैं, जिन्हें संगीत से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए वे पुराने संगीत के रिकार्डों का महत्व भी नहीं समझते। ऐसे में उनका कोई मित्र या रिश्तेदार पुराने संगीत की कापी करना चाहता है, तो वह उसे उसकी मूल कापी ही दे देते हैं।

कला को सरकार से बहुत भारी खतरा है। आकाशवाणी में कई महानिदेशक ऐसे भी आते हैं, जिन्हें संगीत से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए वे पुराने संगीत के रिकार्डों का महत्व भी नहीं समझते। ऐसे में उनका कोई मित्र या रिश्तेदार पुराने संगीत की कापी करना चाहता है, तो वह उसे उसकी मूल कापी ही दे देते हैं।

माया : क्या कोई ऐसा उदाहरण आप देंगे ?

खां : जी हां, ऐसे मंत्री थे, जिन्होंने 'ओरिजनल' ही ले जाने की इजाजत दी। इस प्रकार उस कलाकार का तो इतिहास के पन्नों से नाम ही मिट गया। सरकार की अपेक्षा तो निजी संस्थान अधिक जागरूक हैं। वहां बड़े-बड़े तालों में प्राचीन संस्कृति व संगीत के अवशेषों को हिफाजत से रखा गया है, जबकि सरकार ने जितना ढिंढोरा पीटा है, उतनी हिफाजत में नहीं रखा है।

माया : तो आपका मत है कि जहां तक संभव हो, संगीत को सरकार के हाथों में न जाने दिया जाये।

खां : क्योंकि संरक्षण का खतरा है। आजादी के बाद इन चालीस वर्षों में सरकार ने संगीत-प्रचार, विकास आदि पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि आज के जो भी बड़े या प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जिसने सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे देश में ऐसे ५०,००० संस्थान हैं, जिनको सरकारी सहायता प्राप्त है, फिर क्यों नहीं कोई महान कलाकार निकला.....

माया : आपके विचार में इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ?

खां : गलत पद्धति इसका एकमात्र कारण है। यदि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान सही सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बदला जाये। इसके लिए बड़े कलाकारों से राय लेनी चाहिए। उनसे विचार-विमर्श किया जाये कि किस प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति दी जाये। योग्यता की जांच कलाकारों द्वारा होनी चाहिए। कला को कलाकारों का संरक्षण मिलना चाहिए। वैसे, यह अच्छी बात है कि ७ सांस्कृतिक मंडल बनाये गये हैं।

माया : सांस्कृतिक मंडलों में वही सब खतरे नहीं है ?

खां : इनमें कार्य करने वाले नये लोग हैं। यों भी इनका परिणाम तो ५-१० साल बाद ही पता चलेगा।

माया : कलाओं का वातावरण बनाने में सरकार की क्या भूमिका है ?

खां : जगह-जगह पर उत्सव करके सरकार वातावरण बनाने में पूरी तरह मददगार है।

माया : लेकिन देखा गया है कि इन उत्सवों में या तो लोक कलाकार हैं या प्रसिद्ध कलाकार। बीच के या नये कलाकार शामिल नहीं हो पाते।

खां : नहीं, नये कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए युवाओं के लिए शिकायत का

कोई मौका नहीं है। यहां तक कि पिछली बार फ्रांस उत्सव में बड़े कलाकारों का यह कहकर निरादर ही किया गया कि बूढ़े कलाकारों के स्थान पर युवा कलाकार जायेंगे, सरकार का यह रवैया भी उचित नहीं है।

माया : म०प्र० सरकार से आपका क्या विवाद हुआ था?

खां : मेरा विवाद यही है कि एक प्रांत में जहां २० महान संगीतकार हुए हों, वहां एक ही व्यक्ति के नाम से पीठ बनाया जाये, तो यह दूसरे के लिए निरादर की बात है। सब को समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। यों भी ग्वालियर, जहां संस्कृति व संगीत के इतिहास की जड़ें हैं, मुगल काल में जहां संगीत का जन्म हुआ, उसे ही उजाड़ दिया गया। इसके पीछे राजनीति या कोई अन्य वजह हो सकती है, परंतु एक संगीतज्ञ होने के कारण मुझे बहुत दुख है। भोपाल में जहां संस्कृति की कोई जड़ नहीं है, भारत भवन स्थापित कर दिया गया है।

माया : भारत भवन को कला की राजधानी नाम दिया गया है।

खां : यह विडंबना ही है, जहां एक महान आत्मा लेटी है, उसके ऊपर मकबरा नहीं है और जहां मकबरा बना दिया गया है, उसके नीचे कोई आत्मा नहीं है।

माया : भारत भवन को आप मकबरा ही करार दे रहे हैं?

खां : जी हां, नीचे कोई जड़ नहीं है।

माया : लेकिन कहा जाता है कि इसमें कलाओं की एक आत्मा विकसित हुई है। क्या इससे आप सहमत नहीं हैं?

खां : विकसित हुई या अविकसित, यह तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा।

माया : यानी अब तक का उनका योगदान आप को संतोषजनक नहीं लगा?

खां : नहीं, अभी तक तो उनका योगदान प्रशंसनीय है। अशोक वाजपेयी जब से प्रशासन में आये हैं, कई उत्सवों का आयोजन हुआ है।

खां : परन्तु यदि ग्वालियर में भी कुछ कार्य किये जाते तो खुशी होती। जिन आत्माओं के ऊपर से समाधियां तक उखड़ गयीं, मकबरे टूट गये, वे भी बन जाते। सब से अधिक दुख तानसेन के मकबरे का ही है। उनकी कितनी ख्याति है। संगीत के क्षेत्र में उनका अथाह योगदान है। प्रधानमंत्री से चपरासी तक उनका नाम लेकर गर्व करते हैं। उसी देश में ऐसे महान विभूति के मकबरे की दुर्दशा देखकर सिर शर्म से झुक जाता है।

माया : क्या यह आवश्यक है कि सरकार ही सब कार्य करे, कलाकारों की भी तो कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए?

खां : निस्संदेह, कला का ज्ञाता होने के कारण कलाकार की सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी मात्रा में धन की भी आवश्यकता है। सरकार व लोगों से पैसा इकट्ठा करना कठिन कार्य है। मैं स्वयं यह सोचकर कि अपने बाद की पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा किया जाये, जिससे उन्हें सही दिशा मिल सके, एक संस्थान बनाना चाहता हूं। इसी सिलसिले में नवंबर-दिसंबर में चार महानगरों में कार्यक्रम करूंगा, ताकि संस्थान के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

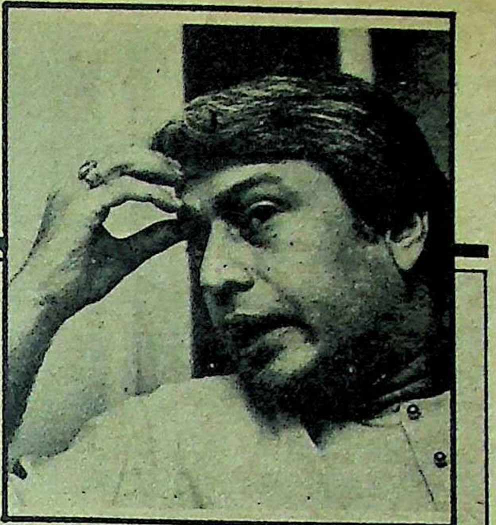

ग्वालियर, जहां संस्कृति व संगीत के इतिहास की जड़ें हैं, मुगलकाल में जहां संगीत का जन्म हुआ, उसे ही उजाड़ दिया गया। इसके पीछे राजनीति या कोई अन्य वजह हो सकती है। परंतु एक संगीतज्ञ होने के कारण मुझे बहुत दुख है। भोपाल में जहां संस्कृति की कोई जड़ नहीं है, भारत भवन स्थापित कर दिया गया है।

माया : व्यावसायिक रूप से आपने पहला सार्वजनिक कार्यक्रम कब दिया था?

खां : पहले के कार्यक्रमों में केवल १००-१५० रूपए ही मिलते थे, जो कि बहुत ही कम थे। इसीलिए उन्हें व्यावसायिक नहीं माना जा सकता। वैसे, मैंने पहली बार ६ वर्ष की आयु में कानसर्ट किया था। हमारे खानदान में स्टेज पर बैठने के तौर-तरीकों की जानकारी के लिए छोटी उम्र से ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था।

माया : अपने बचपन के विषय में कुछ बतायेंगे?

खां : मैंने अपना बचपन दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद कर नहीं बिताया। पूरे लगन से रियाज करता था। मेरे पिता उस्ताद हफीज अली खां खुद एक नामी संगीतज्ञ थे। रियाज के कारण वह हमें स्कूल तक नहीं जाने देते थे। इसीलिए जब तक ग्वालियर में रहे, थोड़े अरसे तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, फिर घर में ही अध्यापक पढ़ाने आते थे।

माया : कौन-कौन से विषय पढ़ते थे?

खां : हिन्दी, जिससे मुझे बेहद लगाव है। अंग्रेजी व उर्दू।

माया : बचपन की कोई ऐसी खास घटना आपको याद है?

खां : आज के माहौल में, जो कि शास्त्रीय संगीत के विरोध में है, शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली आने के बाद मैं माडर्न स्कूल में पढ़ता था। वहां आखिर के दो पीरियड खेल के होते थे। मुझे खेलों में कोई विशेष रूचि नहीं थी, इसलिए प्रिंसीपल से अनुमति लेकर, खासकर सर्दियों के दिनों में मैं रियाज के लिए घर आ जाया करता था। इससे साथियों को बड़ा आश्चर्य होता था, वे सभी अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए सोच भी नही सकते थे कि हम सरोद ही बजायेंगे। खैर, अपने साथियों को खुश करने के लिए मुझे फिल्मी धुनें बजानी पड़ती थीं।

माया : कौन सी फिल्मी धुनें आपको प्रिय थीं तब?

खां : चौंदहवी का चांद हो, डम-डम डिगा डिगा, तेरी प्यारी-प्यारी सूरत को...,ये सभी हिट गानों की धुनें मैं खाली पीरियड में बजाकर सुनाया करता था। वैसे भी, प्रारंभ से ही मेरा मानना है कि बात ऐसी की जाये जो सभी की समझ में आये, क्योंकि संगीत के लिए भी मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उसका निरादर भी नहीं होना चाहिए। किसी कार्यक्रम के दौरान यदि कोई उठकर जाये, तो इसमें उस व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि हममें ही कहीं कोई कमी है, जिससे श्रोताओं को बांध नहीं पा रहे हैं। स्कूली दिनों में मुझे यह नहीं मालूम था कि अपने साथियों को किस प्रकार का शास्त्रीय संगीत सुनाया जाये। इसलिए उनकी खुशी के लिए फिल्मी धुनें ही बजानी पड़ती थीं।

माया : पत्नी से परिचय, कहां व किस प्रकार हुआ?

खां : एक पार्टी के दौरान कलकत्ता में उनसे परिचय हुआ। धीरे-धीरे परिचय प्रेम में बदल गया। वह स्वयं भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं। असम से संबंधित होने के कारण तथा हिन्दू-मुस्लिम जाति भेद के कारण हमारे विवाह में बहुत सी अड़चनें आयीं, काफी तनाव उत्पन्न हुआ।

माया : कहा जाता है कि आपके प्रशंसकों में महिलाएं अधिक हैं। उनकी भावनाओं की वजह से आपको कभी परेशानी नहीं हुई?

खां : शादी के बाद तो नहीं, लेकिन पहले जरूर हुई। वे सभी कटु अनुभव हैं, जिन्हें याद करके मुझे कभी गर्व नहीं हुआ।

माया : आप यदि कलाकार नहीं बनते, तो क्या करते?

खां : नहीं, मैं और किसी लायक नहीं हूं।

माया : दूसरे किन कलाकारों का संगीत आप सुनते हैं?

खां : उस्ताद अब्दुल करीम खां, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, डागर बंधु, श्रीमती केसरबाई केरकर व बनारस की ठुमरी गायिकाओं में रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर...इनका संगीत मुझे प्रिय है।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

—सुप्रिया राय

कुआं देवता

मुहावरा तो है 'नेकी कर, कुएं में डाल' अर्थात् भलाई कर और भूल जा, यहां 'कुआं' एक प्रतीक शब्द है, जिसका अर्थ कुआं नहीं होता, लेकिन अब एक ऐसा वास्तविक कुआं पैदा हो गया है, जिसमें लोग इस विश्वास के साथ सिक्के और करेंसी नोट डाल रहे हैं कि उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जायेंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि निकट भविष्य में इस कुएं की ख्याति इतनी फैल जाये कि लोग मुहावरे की तरह कहने लगें कि 'अपना भला चाहता है, तो कुएं में कुछ (सिक्के) डाल।'

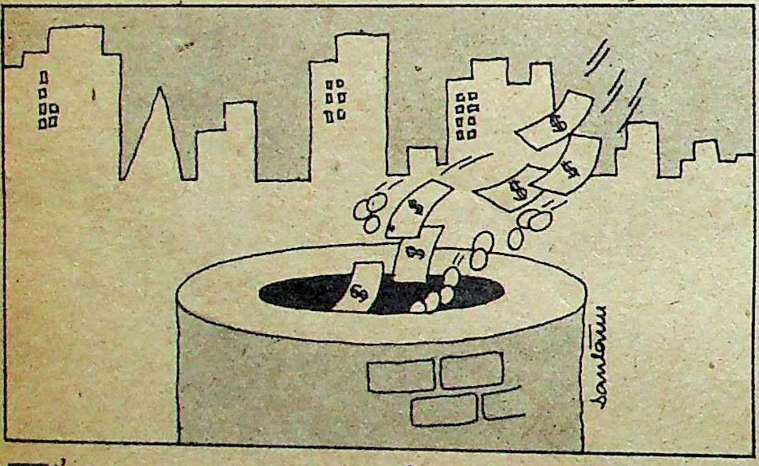

इस कुएं को देखने के लिए युगोस्लाविया के क्रोसिया प्रांत की राजधानी जगरेब चलना पड़ेगा। पांच लाख की आबादीवाले इस शहर के रिपब्लिक चौक पर स्थित यह कुआं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों इस शहर में चल रही विश्व छात्र खेल प्रतियोगिताओं के कारण बाहर से आये खिलाड़ियों और खेल-दर्शकों की भारी भीड़ भी है। जाने कैसे यह अफवाह उड़ गयी कि इस कुएं में सिक्के डालने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कुएं की ख्याति फैलते ही लोग इस उम्मीद में उसमें सिक्के गिराने लगे कि इससे उनकी तमन्नाएं पूरी हो जायेंगी। बहरहाल इस कुएं में दो-तीन दिनों में ही दो टन सिक्के जमा हो गये। जगरेब नगर का प्रशासन हैरान था कि वह इन सिक्कों का क्या करेगा.? उस कुएं में प्रतिदिन इतने सिक्के और करेंसी नोट लोग गिरा रहे हैं कि इनकी गिनती कर पाना किसी व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है; इसलिए स्थानीय अधिकारियों ने इन सिक्कों की गिनती के लिए एक खास किस्म की मशीन लगा दी है। कुएं से इतनी बड़ी मात्रा में सिक्कों का खजाना निकल रहा है कि नगर के अधिकारी इस धन से नगर के पुनर्निर्माण की योजना बनाने लग गये हैं। कुएं के नाम से जगरेब बैंक में एक खाता भी खोला गया है।

सिक्के डालनेवाले इस कुएं को चंद सिक्कों के बदले जाने कितने बड़े-बड़े काम सौंप रहे हैं। पता नहीं, वे काम पूरे होंगे कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भक्तों का यह धन जगरेब नगर की भलाई के काम जरूर आ जायेगा।

विश्व का सबसे धनी व्यक्ति

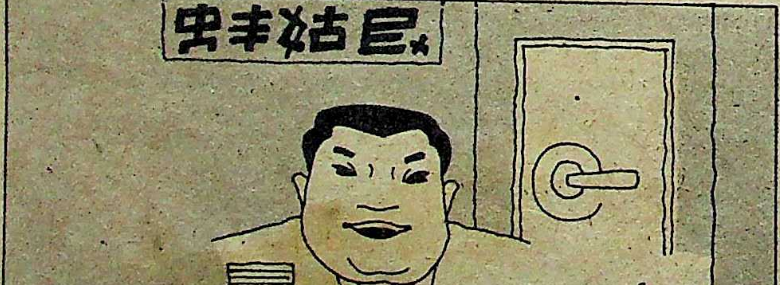

'जिसके पास धन है, उसके पास सब कुछ है'—इस प्रचलित मान्यता के अनुसार जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कहा जायेगा। और आज की दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एक जापानी—जिसका नाम है, योशीयाकी त्सुत्सुमी। इनके पास २१ अरब डालर अर्थात् ढाई खरब रुपए से अधिक की संपत्ति है। योशीयाकी कितने बड़े अमीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि अमरीका के सर्वाधिक धनी व्यक्ति साम मूरे वाल्टन की कुल संपत्ति साढ़े चार अरब डालर अर्थात् करीब ५५ अरब रुपए आंकी गयी है।

एक जमाना था, जब सर्वाधिक अमीर इंग्लैण्ड में हुआ करते थे। उसके बाद अमीरी खाड़ी के देशों में आयी और अरब शेख अरबपति बनते चले गये। यह रेगिस्तान में निकले तेल की कृपा थी, लेकिन आपसी युद्धों ने अमीरी का दर्जा उनसे छीनकर अमरीका को सौंप दिया। यह माना जाता था कि अमरीका में सबसे अधिक धनवान लोग हैं, लेकिन अब जापान ने उनसे यह हक छीन लिया है। न केवल विश्व का सबसे बड़ा अमीर जापान में है बल्कि अमीरों की सर्वाधिक संख्या भी जापान में है।

अमरीका की व्यावसायिक पत्रिका फारबेस ने अमरीका के ४०० सर्वाधिक अमीर लोगों की सूची जारी की थी, जिनमें सिर्फ २१ अरबपति हैं। जापान की जनसंख्या अमरीका से आधी है इसके बावजूद वहां २२ से अधिक अरबपति हैं, जिनमें से अनेक तो खरबपति भी हैं।

गंदगी की खोज

साफ-सुथरा रहना वैसे सबको अच्छा लगता है, लेकिन महिलाएं अधिक सफाईपसंद होती हैं या पुरुष?—इस सवाल के जवाब में पुरुषों की भी यही मान्यता होगी कि महिलाएं तो स्वभावतः सफाईपसंद होती हैं, क्योंकि सफाई का सौंदर्य से अटूट रिश्ता होता है और सुंदर दिखना व सुंदर बनना महिलाओं की प्रकृति में समाया हुआ है। पश्चिमी देशों में चले महिला मुक्ति आंदोलन की कई मुंहफट नेताओं ने तो पुरुषों पर अनेक आरोपों के साथ-साथ यह आरोप भी लगाया कि पुरुष न केवल सफाई-पसंद नहीं होते, बल्कि वे घर में गंदगी भी फैलाते हैं, जिसे महिलाओं को ही साफ करना पड़ता है।

लेकिन असलियत क्या है? ब्रीघम यंग यूनिवर्सिटी के प्रो० प्रेडरसन के नेतृत्व में एक शोध छात्र ने जो असलियत उजागर की वह यह है कि महिलाओं को भी सफाई-पसंद नहीं कहा जा सकता। प्रायः अधिकांश लोगों का आचरण एकांत में बदल जाता है और महिलाएं इसकी अपवाद नहीं हैं।

वह शोध छात्र एक महिला-बाथरूम के प्रतीक्षा कक्ष में छुपकर बैठ गया था। महिलाऐ बाथरूम से निकलती थीं और जब वे पाती थीं कि उन्हें कोई देख रहा है, तो वे हाथ धोती थीं। ऐसी २० महिलाओं में से १८ महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने हाथ धोये। लेकिन शोधार्थी यह देखकर उछल पड़ा कि लोगों की उपस्थिति में जिन २० में से १८ महिलाओं ने अपने हाथ धोये थे, अकेले में लगभग सभी ने हाथ नहीं धोये। अपनी इस 'ऐतिहासिक खोज' के बाद उसने सीना तान कर यह कहना शुरू कर दिया है कि सफाई के मामले में महिलाओं को पुरुषों से बेहतर नहीं कहा जा सकता।

संयोजन : विनोद मिश्र

६ और ७ जुलाई, १९८७ को हताश आतंकवादियों ने तीन बसों पर कायराना हमला करके फिर से अपनी खूनी ताकत दिखाने, प्रचार पाने और देश के अन्य भागों में रह रहे निर्दोष सिखों के खिलाफ नफरत भड़काने की घिनौनी कोशिश की। चंडीगढ़ से ऋषिकेश जानेवाली एक और दिल्ली सिरसा के बीच चलनेवाली हरियाणा रोडवेज की दो बसों के ७६ व्यक्तियों की नृशंश हत्या अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। अपने को सिख-धर्म के रक्षक बतानेवाले इन आतंकवादियों ने ३० जून तक ३९४ लोगों की हत्या की है, जिनमें २२१ सिख थे। इतना ही नहीं, सामूहिक हत्याओं में चुन-चुनकर एक ही समुदाय के लोगों को मारने के पीछे भी इन आतंकवादियों का एक ही नापाक इरादा रहता है—किसी तरह अन्य प्रांतों में रह रहे सिखों के खिलाफ हिंसा भड़के, जिससे वे अपनी जड़ों से उखड़कर पंजाब की ओर भागें। जाहिर है पंजाब में होनेवाली हत्याओं के खिलाफ यदि दूसरी जगहों पर सिखों के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया होती है, तो यह आतंकवादियों की साजिश को सफल बनाना है।

आतंकवादियों ने इन बसों का मारुति कार से पीछा किया और उन बसों को रोक कर यात्रियों को गोलियों से भून दिया। सिरसा से दिल्ली जानेवाली बस की महिला यात्रियों के साथ तो इन आतंकवादियों ने अमानवीय व्यवहार करके उनको मौत के घाट उतारा। लालडू कांड में एक आतंकवादी भी मारा गया, जिसका नाम गुरमीत सिंह उर्फ टोनी (देखिए चित्र) था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपए का इनाम था।

छाया : योग जॉय

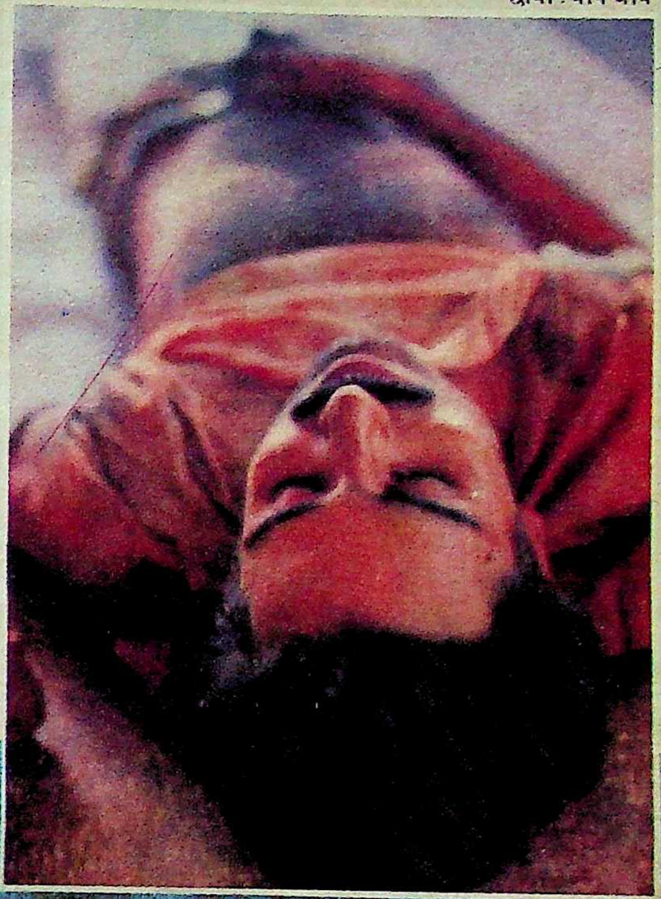

चण्डीगढ
CHANDIGARH
ऋषिकेश
CHANDIGARH

छाया : संजय शर्मा

रूस में एक वर्ष तक चलनेवाले भारत महोत्सव का क्रेमनिल में आयोजित एक विशेष समारोह में ३ जुलाई को राजीव गांधी और रूसी नेता मिखाइल गोर्बाचोफ ने उद्घाटन किया। यह विदेशों में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव है। इस पर १३ करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके तहत रूस के ९० शहरों में कार्यक्रम होंगे। इसमें १७०० कलाकार भाग ले रहे हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के शिखरस्थ कलाकार हैं। राजीव गांधी इस अवसर पर तीन दिवसीय रूस यात्रा पर रहे। रूसी जनता और नेताओं ने उनके प्रति अपूर्व स्नेह और सद्भाव का प्रदर्शन किया।

○ लेनिन स्टेडियम में एक भारतीय लोकनृत्य का दृश्य (बायें ऊपर)
○ राजीव गांधी और सोनिया गांधी का रूसी परंपरा के अनुसार स्वागत। साथ में श्री एवं श्रीमती गोर्बाचोफ (बायें नीचे)
○ समारोह में भाग लेने जाते हुए राजीव गांधी के साथ रूसी नेता (दायें ऊपर)
○ मैत्री और सद्भाव के प्रतीक के रूप में पौधा लगाते हुए (दायें नीचे)

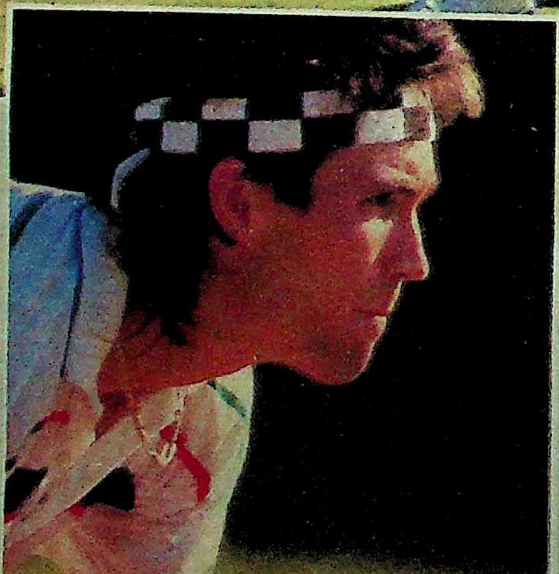

अमरीका की मार्टिना नवरातिलोवा ने इस बार आठवीं बार विंबलडन (लगातार छह बार) खिताब जीता। १९८२ से वह लगातार विंबलडन पर अपना अधिकार जमाये हुए हैं। उन्होंने १९८२ से अब तक लगातार ४१ मैच जीते हैं जो अपने आप में एक रिकार्ड है। उन्हें इस बार इनाम में ट्राफी, १ लाख ३६ हजार ५०० पाउंड स्टर्लिंग (लगभग ३२ लाख रुपए) मिला है। इस तरह टेनिस प्रतियोगिताएं जीतकर अब तक नवरातिलोवा करोड़ों रुपए की राशि अर्जित कर चुकी हैं। वह टेनिस के क्षेत्र की सबसे कमाऊ खिलाड़ी हैं। नवरातिलोवा स्टैफीग्राफ (जिनको उन्होंने फाइनल में हराया) के साथ (ऊपर)। २२ वर्षीय पैट कैश १९७१ के बाद विंबलडन में पुरुष एकल खिताब जीतनेवाले दूसरे आस्ट्रेलियायी खिलाड़ी हैं। उन्होंने विश्वविख्यात और वरीयता में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी इवान लेंडल को हराया। कैश ने जाज्वल्यमनि ट्राफी के साथ एक लाख पचपन हजार पाउंड स्टर्लिंग (लगभग ३४ लाख रुपए) हासिल किये। (नीचे)

स्वादिष्ट कला

मक्खन से सुंदर मूर्तियां बनाने की प्राचीन तिब्बती कला स्वयं एक आश्चर्य है, किंतु इससे भी बड़ा अचरज यह है कि एक सप्ताह के कड़े परिश्रम के बाद लोग इन विचित्र कलाकृतियों को खा जाते हैं।

वृद्ध बौद्ध लामाओं के कथनानुसार यह अनूठी कला लगभग १५०० वर्ष पुरानी है और इसका जन्म भी तिब्बत में ही हुआ। इनका कहना है कि तिब्बत पर चीनी आक्रमण होने तक तिब्बत की कई अनोखी हस्तकलाएं प्रायः सभी मठों में प्रचलित थीं।

दो बौद्ध लामा मूर्तिकार मक्खन की प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त। सामने रखी मूर्तियां मक्खन से निर्मित हैं

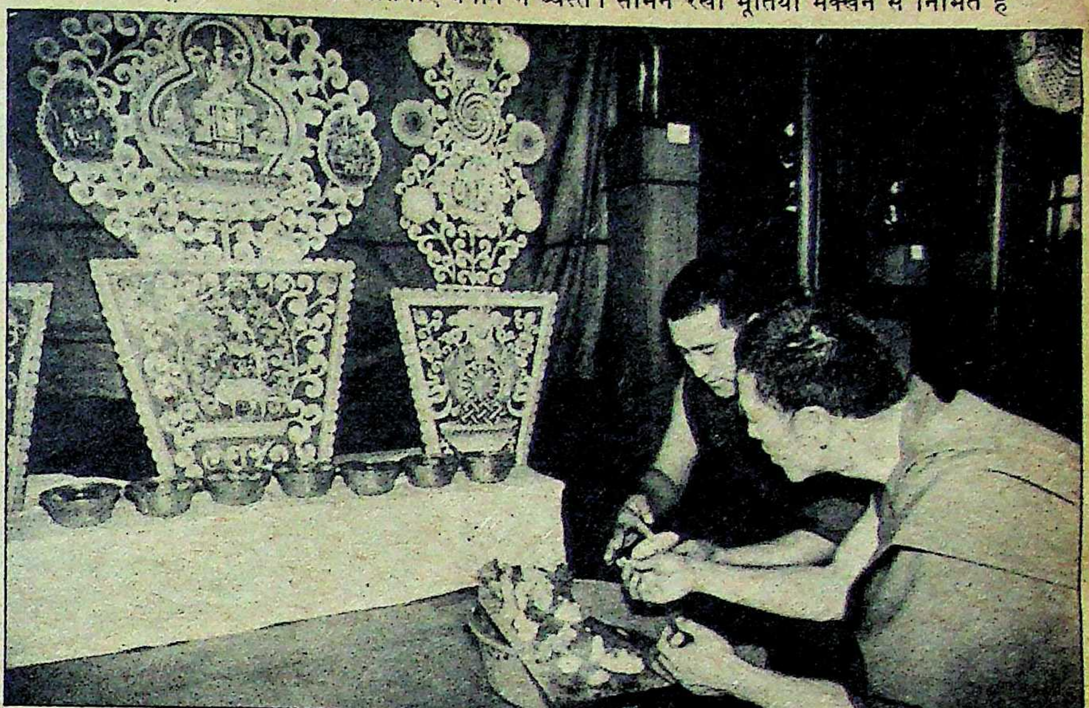

पंद्रह सौ वर्ष पुरानी तिब्बती कला का एक नमूना : मक्खन से तराशी गयी गौतम बुद्ध की प्रतिमा। एक सप्ताह के कड़े परिश्रम से बनायी गयी विचित्र कला-कृतियों को एक जलसे के उपरांत भक्तगण प्रसादस्वरूप खा जाते हैं

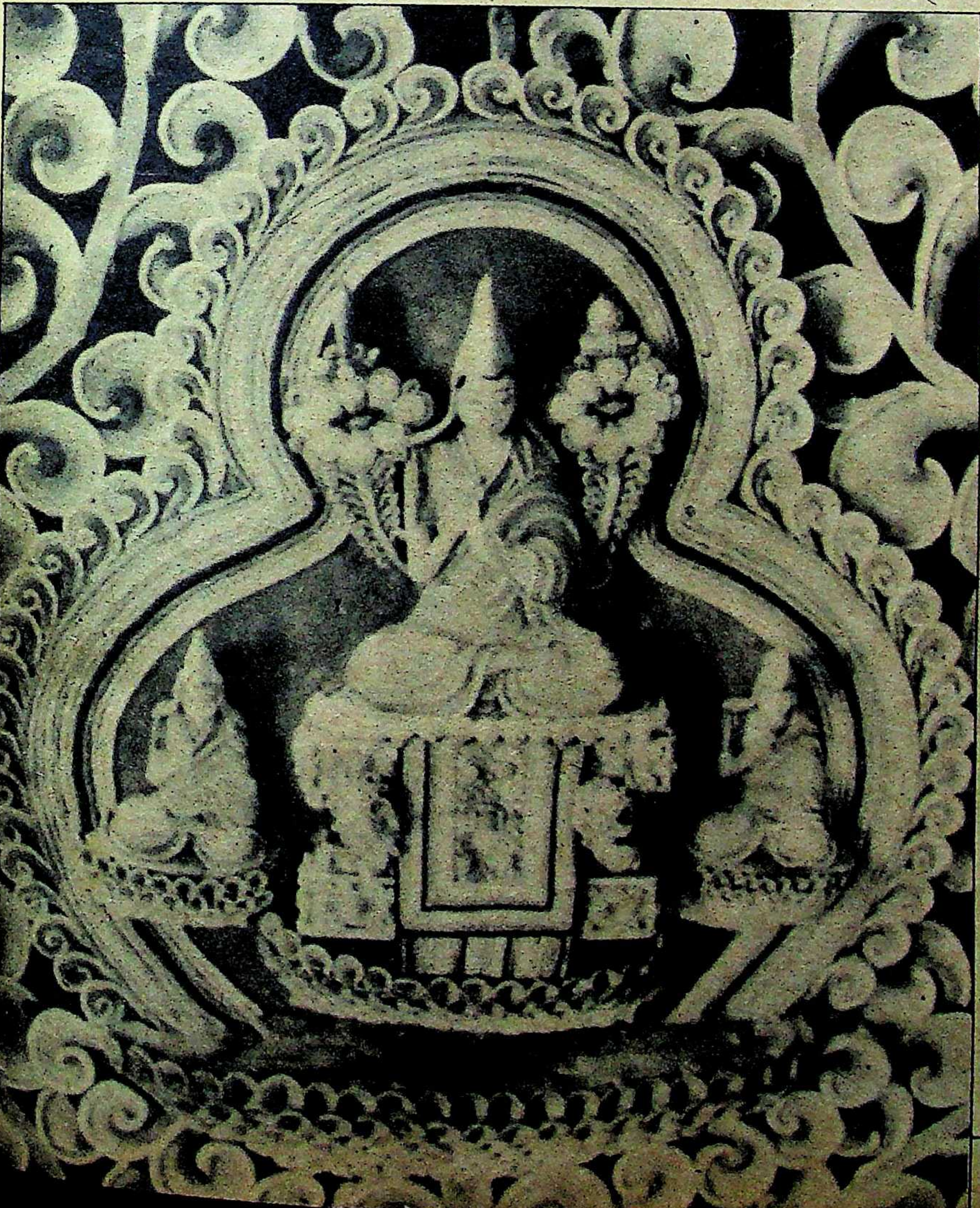

किंतु बाद में पुराने कलाकार-लमाओं को भाग कर भारत या भूटान में शरण लेनी पड़ी।

मकर संक्राति के अवसर पर तिब्बत के प्रत्येक बौद्ध मठ में एक सप्ताह का जलसा होता था, जिसमें भाग लेने दूर-दूर से लोग आते थे। मनों मक्खन (याक के दूध से बना) इकट्ठा कर लिया जाता था, जिसमें कस्तूरी, चंदन-चूर्ण एवं खाड़ मिलायी जाती थी, फिर इससे नाना प्रकार की मूर्तियां बनायी जाती थीं। बहुधा मूर्तियां भगवान बुद्ध, भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्पादि, नाना-प्रकार के दानव या पशु-पक्षियों की होती थीं। एक मूर्ति को बनाने में पांच-सात दिन लग जाते थे। फूल बनाने में एक-एक पंखुड़ी को बारीकी से तराशा जाता था। नक्काशी ऐसी कि ताजमहल भी झेंप जाये। लामा दिमक्षी दुश्चे के अनुसार, "मक्खन को तराशना संगमरमर को तराशने से कहीं अधिक कठिन है उंगलियों का दबाव जरा भी अधिक हुआ, तो सारी मेहनत चौपट।" इस कला में कभी-कभी बनस्पतियों से बने रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु अधिकांश कला-कृतियां मक्खन के प्राकृतिक सफेद रंग की ही होती हैं।

जब मूर्तियां तैयार हो जातीं तो उन्हें मठ के बाहर एक ऊंचे स्थान पर सजा दिया जाता था, प्रार्थना के बाद भक्तगण मूर्तियों को नोच-नोच कर प्रसादस्वरूप खा जाते थे। प्रसाद का कुछ भाग घर भी ले जाते। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत क्षण भर में भक्तों के पेट में चली जाती।

तिब्बत में तापमान ऐसा है कि महीनों तक मक्खन नहीं गलता, किंतु मैदानी इलाकों में इस कला का प्रदर्शन वातानुकूलित कमरे या पंखों के नीचे किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अंतर और है: यहां तिब्बत की भांति याक का मक्खन उपलब्ध नहीं होता।

छाया एवं आलेख : आर० पांडे

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक

रसायनवटी

SAMPAN 342

बढ़ती हुई आयु, रोज़मर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर पूरे शरीर का पोषण कर पूर्ण सशक्त बनाती है। **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ, विश्वसनीय, असरदार एवं बेजोड़ आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो आयु के हर आयाम पर सतत निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
राजवैद्य
शीतल प्रसाद एण्ड संस
23, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

200 गोली पैकिंग रु. 70/-, 60 गोली पैकिंग रु. 27/50 स्थानीय कर अलग। स्थानीय विक्रेता से लें या वी.पी. द्वारा मंगवायें। वी.पी. खर्च रु. 10/- अलग।

निर्माता :
राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23 दरियागंज, नई दिल्ली– 110002
शाखाएं : दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

अब पाइये शरीर का ऐसा आकार जिसकी आपको चाहत रही है...

SMEW के बारबैल एवं डम्बैल्स से

व्यायाम करके.....

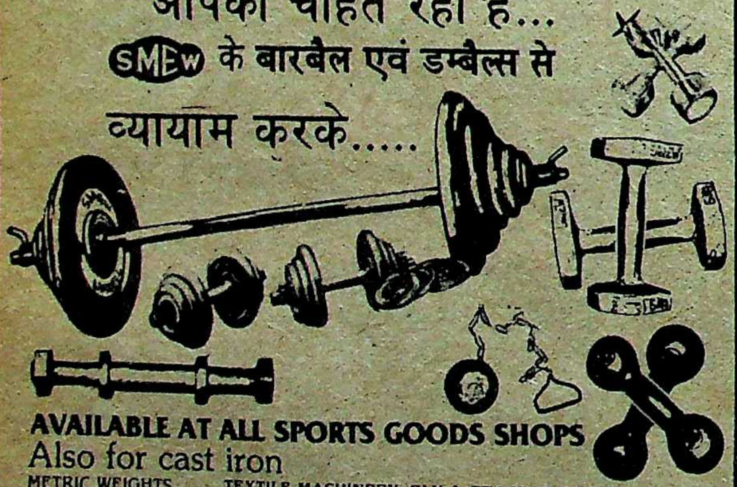

AVAILABLE AT ALL SPORTS GOODS SHOPS

Also for cast iron

METRIC WEIGHTS.
TEXTILE MACHINERY, RLY & TRACTOR PARTS.
TRAPS, CISTERNS & COVERS.
SOIL PIPES AND FITTINGS.
GIRARI, JALI, KHARAL, DURMUT
RAIN WATER PIPES AND FITTINGS.
AGRICULTURAL IMPLEMENTS
GRINDING MEDIA BALLS & CYLPEBS
JOB CASTING

ENQUIRIES & PRICE LIST may be have directly

Gram: 'SILICATE' MANUFACTURED BY:
SHREE MAHAVIR ENGINEERING WORKS
82, Industrial Estate (Nunhai) AGRA-282006
PH: Factory: 72048, 72959, 4542 Residence: 74035, 61721

आप वर-वधु तलाशने का शुभ काम

मनोरमा को सौंपें

'मनोरमा' लाखों-लाख आधुनिक, सुसम्पन्न, सुसंस्कृत व जागरूक परिवारों में रुचि के साथ पढ़ी जाती है। निस्संदेह 'मनोरमा' में छपे विज्ञापन आपको वांछित वर-वधू ढूंढ़ने में मदद करेंगे।

विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं—

३० शब्द तक ३० रुपए, ५० शब्द तक ४० रुपए, ७० शब्द तक ५० रुपए प्रतिवार, बाक्स नं० सहित या छोडकर

अगर आप 'मनोरमा' में वैवाहिक विज्ञापन भेजने के इच्छुक हैं तो विज्ञापन सामग्री के साथ मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के नाम बैंक ड्राफ्ट या क्रॉस्ड पोस्टल आर्डर भेजना न भूलिएगा। नकद रुपये कभी न भेजें, पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट में 'मनोरमा' न लिखें, बल्कि मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड लिखें।

वैवाहिक विज्ञापन तथा शुल्क ड्राफ्ट या पोस्टल-आर्डर द्वारा 'मित्र प्रकाशन प्रा०लि०' के नाम से रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पते पर भेजिए—

वैवाहिक विज्ञापन, मित्र प्रकाशन प्रा०लि०, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद–३

'इंपा' के ५० वर्ष

लेकिन 'रामअवतार एम०एल०ए०' हार गया

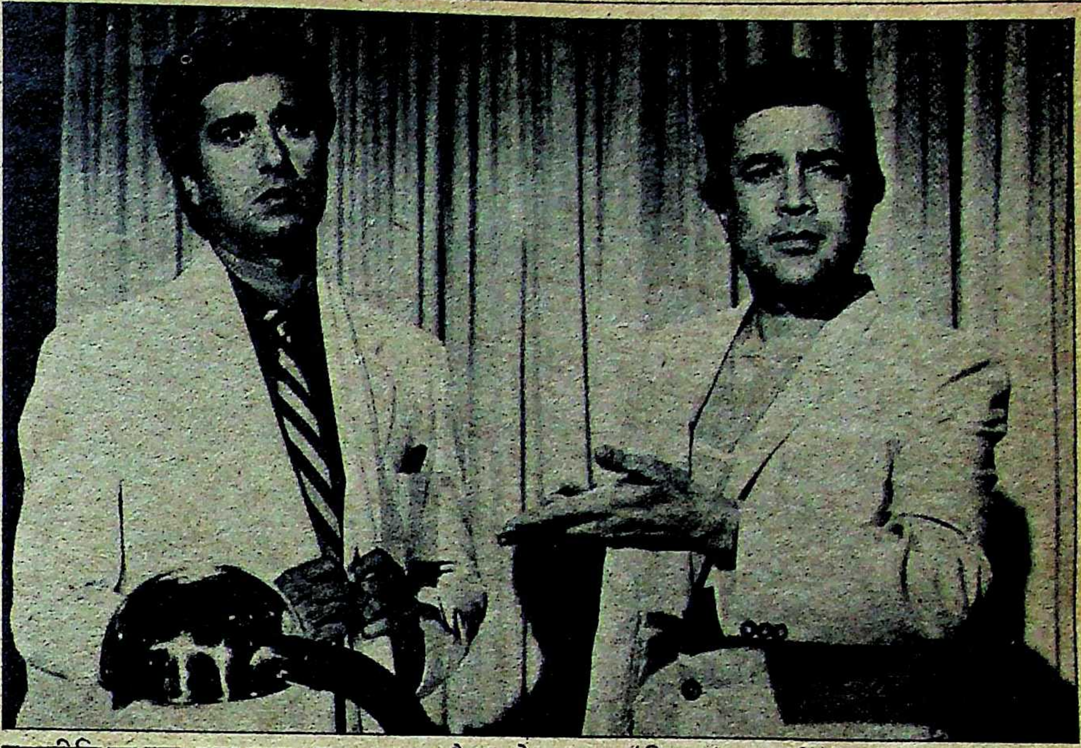

राजनीति का नया-नया साथ : राज बब्बर और राजेश खन्ना (फिल्म 'अवाम' में)

स्वर्ण जयंती वर्ष में हुए 'इंपा' के चुनाव में कांग्रेस-इ के जरिये राजनीति के मैदान में नये-नये आये राजेश खन्ना ने हंगामे के साथ भाग लिया, लेकिन उनके गुट को हार का मुंह देखना पड़ा। राजेश खन्ना गुट की हार के साथ 'इंपा' का असली चेहरा भी उघड़ गया। क्या कारण है कि पचास वर्ष की यात्रा तय करने के बावजूद 'इंपा' फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की संस्था नहीं बन पायी?

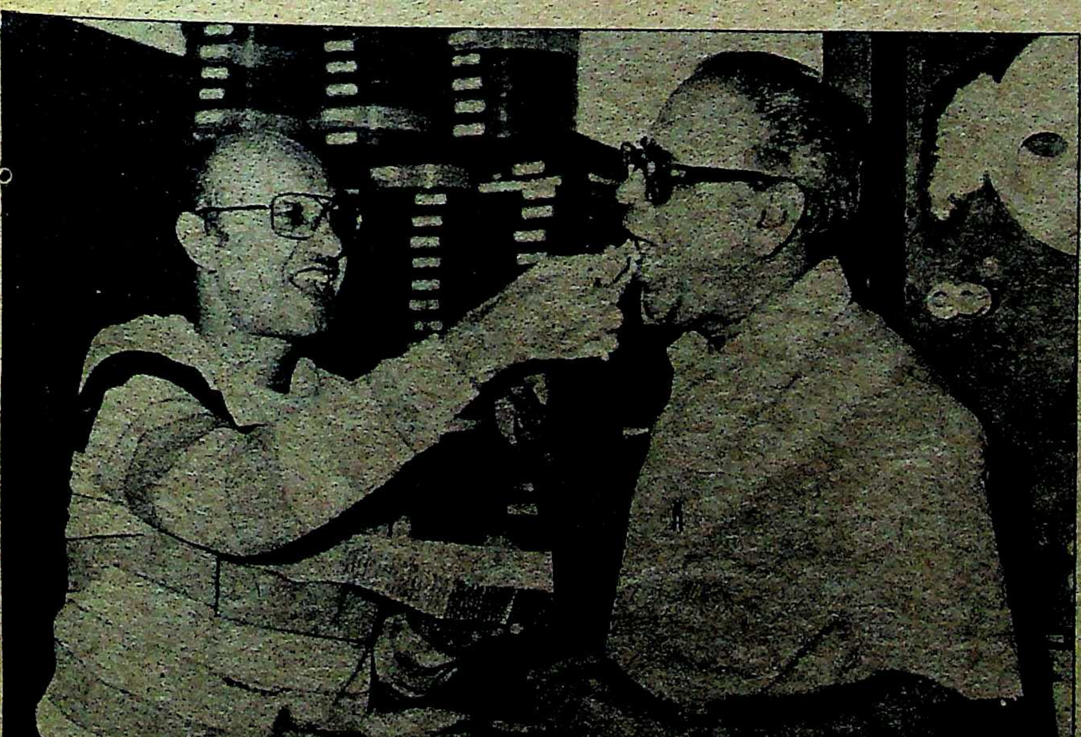

विजय की खुशी : रामराज नाहटा को मिठाई खिलाते हुए मनमोहन देसाई

भारतीय फिल्म निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था 'इंपा' (इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन) के स्वर्ण जयंती वर्ष में, कांग्रेस और राजनीति में नये-नये शामिल राजेश खन्ना ने 'इंपा' का जो चुनाव लड़ा वह इंपा के ५० वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक अभूतपूर्व एवं हंगामेदार रहा। फिल्म के रुपहले परदे पर नकली जिंदगी और नकली राजनीति की ग्लैमरस तस्वीर पेश करनेवाले फिल्म निर्माता पहली बार राजनीति की लड़ाई में शामिल हुए थे, लेकिन मतदान के अंतिम क्षणों (३० जून, १९८७) तक असली मतदाताओं की तरह वे खुलकर सामने नहीं आ सके और हर एक को जिताने का आश्वासन देते रहे थे।

इंपा के इस चुनाव में राजेश खन्ना का प्रोग्रेसिव ग्रुप ५ तथा रामराज नाहटा का युनाइटेड ग्रुप ११ सीटें ले गया। इंपा के चुनाव में अभी तक फिल्म निर्माता उन्हीं को चुनना पसंद करते थे जिनके पास फिल्में नहीं होती थीं और खाली समय होता था। व्यस्त फिल्म निर्माता अपने आपको हमेशा इससे दूर रखते थे, लेकिन १९८५ के इंपा चुनाव में मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, गुलशन राय जैसे अतिव्यस्त फिल्म निर्माता मैदान में आ कूदे, फलतः इंपा की बागडोर श्रीराम बोहरा के हाथ से, जो पिछले दस वर्षों तक इंपा के अध्यक्ष रहे निकल कर रामराज नाहटा के हाथ में आ गयी। मनमोहन देसाई के पक्ष में मतदान करने के लिए अमिताभ बच्चन ने विशेष रूप से फिल्म निर्माताओं को सर्क्युलर भेजे थे। इसी चुनाव के दरम्यान और इसी सर्क्युलर को लेकर प्रकाश मेहरा एवं अमिताभ बच्चन के बीच दरार पैदा हुई, जो अब जाकर खतम हुई।

पिछले वर्ष के चुनाव में रामराज नाहटा के युनाइटेड ग्रुप को सभी १६ सीटों पर अधिकार मिल गया था, लेकिन पिछले वर्ष के अभूतपूर्व सिनेमा बंद और सरकार से हुए समझौते, 'होप ८६' के दौरान एकत्र १ करोड़ ३० लाख रुपए के उपयोग तथा [illegible]

लफड़ा मूवी टावर्स का

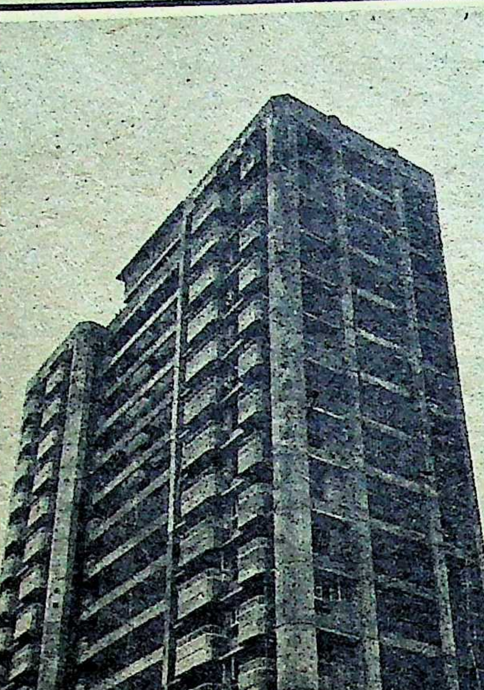

> आज भी फिल्म निर्माता की इस आपत्ति का जवाब इंपा अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में नहीं दे सकी है कि इंपा के तहत बननेवाला यह भवन अचानक और कैसे प्राइवेट सोसाइटी बन गया।

इंपा के ५० वर्ष के कार्यकाल में जितना हंगामा 'मूवी टावर्स' को लेकर हुआ और भू०पू० इंपाध्यक्ष श्रीराम बोहरा और कोषाध्यक्ष फिल्म निर्माता टी०सी० दीवान को जितनी आलोचना सहनी पड़ी उतनी किसी और मामले में संभवतः नहीं सहनी पड़ी होगी। इंपा के चुनाव के ऐन मौके पर मूवी टावर्स का उद्घाटन महाराष्ट्र के वित्तमंत्री सुनील कुमार शिंदे से कराया गया। महाराष्ट्र की राजनीति एवं सरकार में सिर्फ सुशील कुमार शिंदे ही एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो राजनीतिज्ञों से कम, फिल्मवालों से ज्यादा रसूख रखते हैं।

श्रीराम बोहरा तथा टी०सी० दीवान ने १६ दिसंबर, १६८१ को एक बैठक में जब फिल्मवालों के लिए ६६ फ्लैटोंवाली एक गगनचुंबी इमारत के निर्माण का निर्णय किया तो सभी ने उनकी सराहना की। बैठक में निश्चय किया गया कि फ्लैट उन लोगों को आवंटित किये जायें जिनकी अर्जी एवं एडवांस की रकम पहले आ जाये। आपेरा हाउस, जहां इंपा का कार्यालय है, स्थित आंध्र बैंक में इसके लिए एक एकाउंट भी खोल दिया गया। एक-एक हजार वर्गफुट के ३ बेडरूम हालयुक्त फ्लैटोंवाली इमारत का नाम मूवी टावर्स रखा गया।

२५० रुपए प्रति वर्ग गज के भाव से बुक होनेवाले इन फ्लैटों को लेने के लिए फिल्म निर्माताओं में होड़-सी मच गयी और देखते-देखते सारी फ्लैटें बुक हो गयीं। मूवी टावर्स के निर्माण की जिम्मेदारी श्रीराम बोहरा एवं टी०सी० दीवान पर डाल दी गयी। उस समय इंपा में श्री बोहरा एवं दीवान का वर्चस्व था, लेकिन इंपा ने एक अड़ंगा लगाया कि कौंसिल के नियम के अनुसार वे किसी प्रोजेक्ट का खाता संगठन के नाम से नहीं खोल सकते, इसलिए आंध्र बैंक में खाता मूवी बिल्डर्स के नाम से खोला गया। श्रीराम बोहरा ने मूवी टावर्स के निर्माण के औचित्य में इंपा के मेमोरेंडम के क्लाज १७ का हवाला दिया जिसके अनुसार मीटिंग हाल, क्लब, सदस्यों के रहने के लिए फ्लैट, फिल्म निर्माताओं, वितरकों एवं प्रदर्शकों के लिए कार्यालयों का निर्माण किया जा सकता है।

इंपा के उपरोक्त क्लाज के बावजूद मूवी टावर्स के लिए इंपा के नाम से बैंक में एकाउंट खोलने संबंधी अड़ंगे फिर मूवी बिल्डर्स के नाम से एकाउंट खोलने, जिसे संचालित करने का अधिकार सिर्फ श्री बोहरा एवं श्री दीवान को था, पर दूसरे निर्माताओं ने आपत्ति उठायी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। कुछ सदस्यों ने इस बात पर भी ऐतराज किया कि इंपा और फिल्म इंडस्ट्री एजुकेशन एंड चिल्ड्रेंस ट्रस्ट से रुपए निकाल कर मूवी टावर्स के निर्माण में खर्च किये जा रहे हैं। उनकी आपत्ति का आधार यह था कि अगर दोनों संगठनों के कोषों से पैसे खर्च किये जा रहे हैं, तो फ्लैट का रेट चार वर्ष के भीतर २५० रुपए प्रतिवर्ग गज से बढ़ाकर ६०० रुपए क्यों कर दिया गया जबकि मूवी टावर्स न तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और न ही कार्मशियल कांप्लेक्स। रिहायशी फ्लैट्स होने पर भी भाव बिना सदस्यों से विचार-विमर्श किये बढ़ा दिये गये साथ ही ब्याज की राशि भी। चरित्र अभिनेता जानकी दास ने विरोध का झंडा खड़ा किया और नये चुनाव कराने तथा फ्लैटों को शीघ्र दिये जाने की मांग की। उन्होंने शक्ति सामंत से लेकर राजकुमार कोहली आदि निर्माताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया।

पिछले वर्ष जब मूवी टावर्स के सदस्यों को उस आशय की नोटिस मिली कि फ्लैट की कीमत के अलावा उन्हें १ लाख २२ हजार रुपए (८२ हजार रुपए ब्याज के तथा ४० हजार रुपए जमीन-दर में हुई वृद्धि की राशि) अतिरिक्त जमा करने होंगे, तो सदस्यों में बौखलाहट-सी आ गयी। इसका खमियाजा भुगतना पड़ा श्री बोहरा एवं श्री दीवान को। फिल्म निर्माताओं ने उन पर बेइमानी और धोखेबाजी का आरोप लगाया। प्रख्यात फिल्म निर्देशक-वितरक-प्रदर्शक एफ०सी० मेहरा ने यहां तक कह दिया, "यह साफ धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें करोड़ों रुपए का घपला है। मूवी टावर्स का मामला अगर सी०बी०आई० या अदालत में जाये तो सारी बातें उजागर हो सकती हैं।" शत्रुघ्न सिन्हा के सचिव एवं फिल्म निर्माता पवन कुमार का कहना था, "बाजार-भाव के बढ़ने का बहाना देकर ही इन लोगों ने हमसे तमाम धन वसूल कर लिये। हम इस बारे में जब भी उनसे बात करते, वे कहते अगर इस बढ़ी हुई राशि का हम निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करेंगे तो एग्रीमेंट रद्द हो जायेगा।" जाने-माने निर्माता एन०पी० सिंह का कहना था, "हमने एसोसियेशन पर विश्वास कर ढाई लाख रुपए दिये, अब और सवा लाख देना पड़ रहा है। इतनी राशि मैं फिल्म निर्माण या किसी और व्यापार में लगाता तो आज मैं कई गुना अधिक कमा चुका होता।"

लेकिन श्रीराम बोहरा इन सारे आरोपों का खंडन करते हैं, "पिछले छह वर्षों में हर चीज की कीमत और बाजार-भाव आकाश चूमने लगा है। फिर बंबई में जमीन के भाव की वृद्धि की तो बात ही मत पूछिए। लोगों का यह आरोप बेबुनियाद है कि मैंने या किसी ने पैसे खाये, बेइमानी या धोखाधड़ी की। अगर किसी को शक होता तो वह अदालत में जा सकता था, लेकिन पिछले छह वर्षों में किसी ने अदालत जाने या जांच-पड़ताल की जरूरत नहीं समझी। इससे साफ लगता है कि कुछ लोग सिर्फ हमें बदनाम कर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं।"

लेकिन शक्ति सामंत से लेकर राजकुमार कोहली जैसे प्रख्यात निर्माता-निर्देशकों को अब भी शिकायत है कि मूवी टावर्स के निर्माण में जानबूझकर विलंब किया गया, जबकि एग्रीमेंट के अनुसार एक वर्ष के भीतर फ्लैट मिल जाने चाहिए थे। बहुत से फिल्म निर्माताओं ने अपने पैसे वापस ले लिये और फ्लैट ज्यादा पैसे लेकर दूसरों को बेच दिये गये।

जिस समय वरसोवा में मूवी टावर्स बनाने का फैसला किया गया था, यह अविकसित जमीन थी, लेकिन पिछले छह वर्षों में वरसोवा का लोखंडवाला कांप्लेक्स बंबई के सर्वाधिक महंगे (१००० रुपए से १५००० रुपए प्रति वर्ग गज) एवं पोश इलाकों में गिना जाने लगा।

लेकिन आज भी फिल्म निर्माताओं की इस आपत्ति का जवाब इंपा अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में नहीं दे सकी है कि इंपा के तहत बनने वाला यह भवन अचानक और कैसे प्राइवेट सोसाइटी बन गया। यों राजेश खन्ना अगर जीतते, तो जरूर इस सवाल का जवाब देते, क्योंकि उनका नया मकान मूवी टावर्स से थोड़ी ही दूर पर बना है।

—बंबई ब्यूरो

'८७ से शुरू हड़ताल तथा अन्य समस्याओं को लेकर उनमें दरार पड़ गयी। इस दरार का फायदा उठाकर राजेश खन्ना ने इंपा के चुनाव में भाग लेने की घोषणा कर दी और रामराज नाहटा के विरुद्ध अपने प्रोग्रेसिव ग्रुप का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। धर्मेंद्र, राज बब्बर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, रणधीर कपूर आदि फिल्म कलाकारों ने भी चुनाव-प्रचार में भाग लिया। कुछ ने नाहटा ग्रुप का साथ दिया, तो कुछ ने राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना गुट की हार के बाद राज बब्बर ने कहा, "ठीक है, इस बार पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन देखता हूं लोग अगले वर्ष कैसे हराते हैं भला!"

'सिनेमा बंद' के आयोजकों, जिनमें रामराज नाहटा एवं राजेश खन्ना दोनों शामिल थे, से सख्त नाराज अमिताभ बच्चन ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को दी गयी ३० करोड़ रुपए की राहत को फिल्म उद्योगवाले निगल गये और यह राहत फिल्म कामगारों तक नहीं पहुंचायी गयी। अमिताभ बच्चन ने अपने आरोप में उन दो लाख रुपए की भी चर्चा की, जिसे उन्होंने कामगारों के लिए दिया था।

अमिताभ बच्चन के रुख को देखते हुए मनमोहन देसाई, सुभाष घई और अमिताभ गुट के लोग न्यूट्रल हो गये, लेकिन इनमें से कोई भी (अमिताभ भी) राजेश खन्ना को पसंद नहीं करता था, इसलिए अपना परोक्ष समर्थन रामराज नाहटा को दिया। बासु चटर्जी, गुलशन राय जैसे लोग अपनी लोकप्रियता के बावजूद इसी गुट की वजह से हार गये, क्योंकि इनसे अमिताभ बच्चन का बहुत पहले मनमुटाव हो चुका था। राजेश खन्ना गुट के विजयी फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा, हरमेश मल्होत्रा, राजकुमार कोहली एवं पहलाज निहलानी को इस गुट से कोई शिकायत नहीं थी। रामराज नाहटा गुट के विजयी दारासिंह, राजकुमार बड़जात्या, प्राणलाल मेहता, सुरेंद्र मोहन, गुल आनंद, बी०के० आदर्श, अनिल गांगुली, सुल्तान अहमद, राहुल रवेल तथा जानी बख्शी को मनमोहन देसाई एंड पार्टी का अपरोक्ष समर्थन प्राप्त था।

इंपा के चुनाव में पहले जहां बड़ी मुश्किल से ६०-७० फिल्मनिर्माता मतदान के लिए आते थे, वहां इस बार २८४ फिल्म निर्माता आये। मतदान से एक दिन पहले २९ जून, १९८७ की रात को अपनी-अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए रामराज नाहटा ग्रुप ने होटल सेंटोर में तथा राजेश खन्ना ग्रुप ने 'हालीडे-इन' में शानदार पार्टी का आयोजन किया। मेहमानों ने दोनों पार्टियों में शिरकत की, दोनों पक्षों को अग्रिम बधाइयां दीं, लेकिन अधिकांश ने रिश्ते खराब होने के भय से मतदान में भाग ही नहीं लिया।

"मुझे कम सीटें मिलने का गम नहीं है" राजेश खन्ना ने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद 'माया' को बतलाया, "जहां कुछ लोगों की शत-प्रतिशत मेजारिटी हो, उसमें से १६ में से ५ सीटें पा जाना कम महत्वपूर्ण बात नहीं। अगले चुनाव में हमें पूरी १६ सीटें मिल जायेंगी। दरअसल, हमारे यहां अधिकांश फिल्म निर्माता संगठन के काम के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अपनी मनमरजी करते रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा मनोरंजनकर, आयकर तथा दूसरे कर देने के बावजूद फिल्मवालों की बात किसी भी हलके में नहीं सुनी जाती। मैं पूरा वर्ष फिल्म इंडस्ट्री के कल्याण के लिए काम करूंगा और सभी फिल्म निर्माताओं में जागरण पैदा करूंगा कि अगले आम चुनाव में वे तथा संगठन के काम आगे आयें। इंपा एक बहुत बड़ी संस्था है और उसकी बागडोर सही लोगों के हाथ में होनी चाहिए।"

हार की भूमिका : इंपा के चुनाव में १ जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। राजेश खन्ना शुरू से कहते आ रहे थे कि अगर उनका गुट चुनाव जीतेगा, तो वह हड़ताल नहीं होने देंगे और फिल्म कामगारों से मिलकर मामले को सलटा देंगे, जबकि रामराज नाहटा ग्रुप हड़ताल के पक्ष में था। नाहटा ग्रुप का कहना था कि अगर कामगारों की मांगें मान ली गयीं, तो फिल्म का बजट बढ़ जाने से बेचारे छोटे फिल्म निर्माता 'मर' जायेंगे, क्योंकि स्टारकास्ट न होने से उनकी फिल्मों को न तो डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाते हैं न ही फायनेंसर। राजेश खन्ना को मात देने के लिए उन्होंने एक और गोटी चली। कामगारों के फेडरेशन के सामने अपनी मांगें रख दीं—फिल्म कलाकार अपने मेकअप मैन, हेयरड्रेसर, ड्राइवर का लंच तथा कार के पेट्रोल खर्च का भुगतान करेंगे, फिल्म निर्माता नहीं, क्योंकि कलाकार अपने मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर खुद रखते हैं। दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री की तरह अब म्यूजिशियनों को चार के बजाय साढ़े सात घंटे (आधा घंटा 'लंच-ब्रेक' देने पर आठ घंटे) की शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। इस पर म्यूजिशियनों ने अपना रेट दुगुना कर देने की मांग की।

नाइंसाफी में 'इंपा' के साथ नहीं : देवआनंद

नाहटा ग्रुप को जितानेवाले यही छोटे निर्माता थे, जिनको डर था कि राजेश खन्ना ग्रुप के जीत जाने पर उन्हें कामगारों का वेतन बढ़ाना पड़ेगा तथा और भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इन छोटे निर्माताओं का गढ़ नाज सिनेमा कंपाउंड है। नाज सिनेमा के पीछे मनमोहन देसाई का भी कार्यालय है जहां राजेश खन्ना के विरुद्ध परोक्ष मुहिम चलती थी। दूसरी तरफ राजेश खन्ना गुट के समर्थक ज्यादातर बड़े फिल्म निर्माता थे जो अल्पसंख्यक थे। राजेश खन्ना से खार खाये निर्माताओं को भी उन्हें सबक सिखाने का मौका मिल गया था।

फिल्म कामगार (साजिंदे, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, फाइटर, कारपेंटर, लाइटमैन, जूनियर आर्टिस्ट) अपनी दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग महाराष्ट्र सरकार से सिनेमा बंद का समझौता हो जाने के बाद से ही करते आ रहे थे, लेकिन इंपा शुरू से ही इसे टालती रही। फिल्म प्रोड्यूसर कौंसिल ने २५ प्रतिशत वृद्धि की बात मान भी ली, लेकिन फिल्म निर्माताओं में आपसी मतभेद के कारण समझौता नहीं हो सका। फिल्म कामगारों की संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने 'माया' को बतलाया, "कुछ फिल्म निर्माताओं का रवैया शुरू से ही हठधर्मिता से भरा रहा। महाराष्ट्र सरकार से फिल्म निर्माताओं का समझौता हो जाने पर उन्हें काफी राहत और फायदा मिला था, लेकिन उन्होंने उनमें से एक भी हिस्सा फिल्म कामगारों को देने की नीयत नहीं बरती जबकि सिनेमाबंद की सफलता में कामगारों का सबसे बड़ा हाथ था। अगर वे साथ नहीं देते, तो फिल्म निर्माता अपनी आपसी फूट के कारण कभी भी हड़ताल को सफल नहीं बना सकते थे।"

अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म उद्योग पर २९ जून को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार से हुए समझौते के कारण उन्हें ३० करोड़ रुपए की जो राहत मिली उसे वे हड़प ले गये और कामगारों को कुछ भी नहीं दिया। अमिताभ बच्चन ने खुद कामगारों के लिए २ लाख रुपए दिये थे, वह भी कामगारों को नहीं बांटा गया। अभिनेता निर्देशक देव आनंद ने इंपा द्वारा १ जुलाई से शुरू हड़ताल का बहिष्कार करने का निश्चय किया। उनका 'माया' को कहना था, "कामगार अगर अपना हक मांगते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? उनकी समस्या को हल करने के बजाय कामकाज बंद करने का फैसला करना इंपा की सरासर नाइंसाफी है और मैं इस नाइंसाफी में इंपा का साथ कतई नहीं दूंगा और इसके विरोध में शूटिंग करूंगा।"

'होप ८६' में एकत्र डेढ़ करोड़ रुपए के उपयोग का सवाल उठाते हुए फिल्म निर्माता आत्माराम ने 'माया' को बतलाया, "हम सबने मिलकर यह धनराशि एकत्र की थी कि जरूरतमंद कामगारों को इससे सहायता मिलेगी, लेकिन उन रुपयों का क्या हुआ, किन को बांटे गये रुपए?" आत्माराम ने कुछ समय पहले इंडस्ट्री वेलफेयर ट्रस्ट को एक खुला पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जरूरतमंद दो जूनियर आर्टिस्टों—अलीम लाला तथा किशन जे० अरोड़ा को मदद न देने का सवाल उठाया था। आत्माराम का कहना था, "अलीम लाला (६० वर्ष) को कैंसर हो गया था। बंबई के अस्पतालों में हड़ताल होने के कारण [illegible] २६ मार्च, १९८७ को आशा पारेख अस्पताल, सांताक्रुज

में भर्ती किया गया। उनका चिकित्सा संबंधी बिल ११७४ रुपए का भुगतान न हो पाने के कारण उन्हें ६ अप्रैल को अस्पताल छोड़ देना पड़ा। दवा और चिकित्सा के अभाव में १८ अप्रैल को उनकी मौत हो गयी। इसी तरह २० वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किशन जे० अरोड़ा (४४ वर्ष) को २१ अप्रैल, १९८७ को लकवे का दौरा पड़ा। उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां ११ मई, १९८७ को उनकी मौत हो गयी। ट्रस्ट से (इस ट्रस्ट का संचालन इंपा करती है) इन दोनों कामगारों की सहायता के लिए तमाम अपीलें की गयीं, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। दो और जूनियर आर्टिस्ट अपनी लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मांगने गये तो उन्हें भगा दिया गया।"

इंपा की अकर्मण्यता पर ये सवाल कोई पहली बार नहीं उठे थे। प्रख्यात फिल्म पत्रकार एवं कला फिल्म आंदोलन से जुड़े 'स्क्रीन' के संपादक बी०के० करंजिया ने इंपा की चर्चा चलने पर कहा, "मुझे इंपा से बहुत सारी उम्मीदें थीं। इतनी क्षमताशाली, सभी सुविधाओं से सपन्न सस्था फिल्म उद्योग की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी। अपने गठन के ५० वर्ष बाद भी यह संस्था वहीं-की-वहीं है। यह क्या कम अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि जिस उद्योग ने हिंदी का व्यापक प्रसार कर राष्ट्रीय एकता की जोत जलाने का काम किया खुद उसी में एकता का अभाव रहा। पिछले पचास वर्षों में यह इंडस्ट्री इंपा के सहारे नहीं, भगवान के सहारे चलती रही है और चलती रहेगी...।"

इंपा का गठन : ५० वर्ष पहले ५ मई, १९३७ को इंपा का गठन बंबई के तत्कालीन सात फिल्मकारों ने मिलकर किया था। इनमें अर्देशिर ईरानी, जे०बी० एच० वाडिया तथा एम०ए० फजल भाई जैसे विख्यात फिल्मकार थे। (संस्था का रजिस्ट्रेशन ८ अक्तूबर, १९३८ को हुआ था।) हालीवुड तथा लंदन की फिल्म निर्माताओं की संस्थाओं की कार्यपद्धति तथा उन्हें सरकारी, गैरसरकारी संगठनों से मिलनेवाली सुविधाओं ने भारत में अपना खुद का एक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था। उस समय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री न केवल प्रारंभिक चरण में असंगठित थी बल्कि ब्रिटिश सरकार तथा हुक्मरानों की निगाह में इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं थी। कुछ समय पहले जे०बी० एल० वाडिया ने इंपा के गठन की चर्चा करते हुए कहा था, "हम कलाकार ठहरे, लोगों का मनोरंजन करना हमारा तब भी धर्म था और आज भी है। मैं और अर्देशिर ईरानी एक बार लंदन गये, तो वहां की फिल्म निर्माताओं की संस्था के अध्यक्ष ने हमें चाय पर आमंत्रित किया और हमारी फिल्म-इंडस्ट्री के बारे में बात की, जो उस समय इंडस्ट्री नहीं थी। उन्होंने हमें फिल्म निर्माताओं की संस्था बनाने तथा इस इंडस्ट्री को संगठित तरीके से चलाने की सलाह दी। एक वर्ष बाद हमारी मुलाकात सेंचुरी फाक्सवालों से भी हुई। हमने महसूस किया कि अगर हम एक कारगर संगठन बनायें तो बहुत से फिल्म निर्माताओं की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अपनी समस्याओं पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम लोगों को एक साथ बैठने-मिलने का बहाना मिल सकता है।"

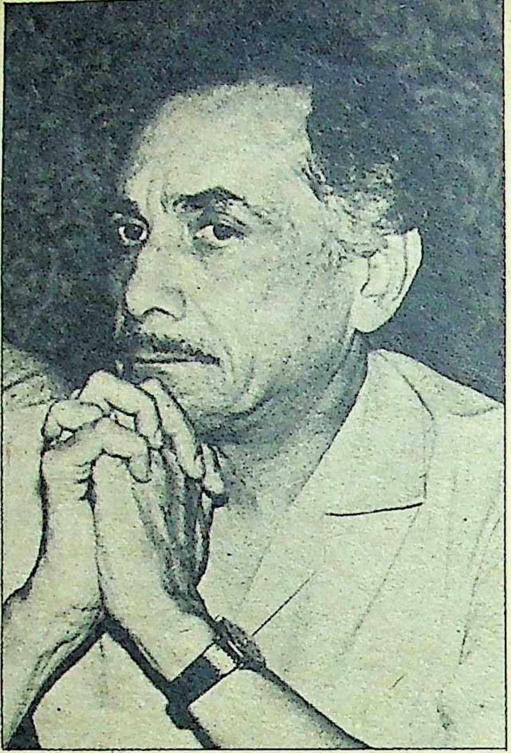
उम्मीदों पर धूल : करंजिया

दादा साहब फालके ने १९१२ में प्रथम हिंदी व भारतीय फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' का निर्माण कर भारत में फिल्म निर्माण परंपरा की उस समय शुरुआत कर दी थी, जब बहुत से राष्ट्रों ने कैमरे का मुंह भी नहीं देखा था। इसके २५ वर्ष बाद भी जब भारतीय फिल्मों को कोई मान्यता और प्रतिष्ठा नहीं मिली, तो १९३१ में पहली बार अर्देशिर ईरानी जे०बी०एच० वाडिया आदि कई फिल्म निर्माताओं ने इस समस्या पर मिलकर विचार-विमर्श किया। भारतीय फिल्मकारों की उस समय सबसे बड़ी समस्या थी—बड़ी तेजी से जड़ें जमाती जा रहीं विदेशी फिल्में। देश के ७०० सिनेमाहालों में से ६५० सिनेमा हालों में विदेशी (अंग्रेजी) फिल्में ही दिखलायी जाती थीं।

इत्तिफाक से १९३१ के बाद कई फिल्मकारों को विदेश यात्रा का मौका मिला और उन्होंने इंपा के गठन की जरूरत महसूस की। इंपा के गठन के बाद उसकी जड़ें मजबूत करने में सरदार चंदूलाल शाह, राय बहादुर चुन्नीलाल, दलसुख एम० पंचोली, महबूब खान, के०एम० मोदी, एस०के० पटेल, बिमल राय आदि ने आगे चलकर काफी योगदान दिया। यह वह समय था जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत-सी चिरस्मरणीय फिल्मों का निर्माण किया। कलकत्ता में न्यू थियेटर्स ने 'चंडीदास', 'देवदास', 'प्रेसिडेंट', 'मेरी बहन', 'मुक्ति' आदि फिल्मों का; पूना में प्रभात फिल्म्स ने 'आदमी', 'पड़ोसी', 'दुनिया न माने' आदि; मद्रास ने 'चंद्रलेखा', 'रतन' आदि; बंबई में बांबे टाकीज ने 'अछूत कन्या', 'बंधन', 'झूला', 'कंगन', 'किस्मत' आदि, सोहराब मोदी ने 'पुकार', 'सिकंदर', विजय भट्ट ने 'रामराज्य' आदि अमर फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों के जरिये भारतीय फिल्म निर्माता, अंतरराष्ट्रीय फिल्म के क्षितिज तक जा पहुंचे।

लेकिन विभाजन के बाद फिल्म निर्माण का व्यवसायीकरण हो गया और इंपा के नेतृत्व की बागडोर सार्थक एवं सक्रिय फिल्म निर्माताओं के हाथ से निकल कर ऐसे फिल्म निर्माताओं के हाथ में पहुंच गयी, जिन्हें फिल्म उद्योग के सामूहिक कल्याण की चिंता नहीं थी। इंपा के भू०पू० अध्यक्ष सरदार चंदूलाल शाह का अधिकांश समय घुड़दौड़, सट्टा और शेयर बाजार में निकल जाता था। (स्व०) आई०एस० जौहर इंपा के अध्यक्ष की कुरसी पर बैठकर पागलपने और बेतुके वक्तव्य जारी करने और उन्हें छपा कर प्रचार हासिल करने में ज्यादा समय लगाते। एक दशक से अधिक समय तक इंपा के अध्यक्ष रहे श्रीराम बोहरा ने सूचनामंत्रियों, सरकारी अधिकारियों की अगवानी करने, उनके सम्मान में मीटिंग आयोजित करने तथा कभी-कभी प्रतिनिधि मंडल लेकर दिल्ली जाने के अलावा कुछ भी सार्थक काम नहीं किया।

इंपा धीरे-धीरे अंदरूनी राजनीति, अव्यवस्था और गुटबाजी का अड्डा बन गया। इंपा को सुधारने की कसम खाकर इंपा अध्यक्ष बने जे० ओमप्रकाश ने २९ दिनों के भीतर ही त्यागपत्र दे दिया। नर्गिस ने भी इंपा के आधुनिकीकरण की कोशिश की और अंततः निराश हो इंपा से त्यागपत्र दे दिया। इंपा की अंदरूनी राजनीति से परेशान होकर व्ही० शांताराम, राज कपूर, एल०वी० प्रसाद, जी०पी० सिप्पी, बी०आर० चोपड़ा ने इंपा से किनारा कस लिया। कुछ प्रमुख फिल्म निर्माताओं ने अपनी अलग फिल्म प्रोड्यूसर्स कौंसिल तथा युनाइटेड इंडिया प्रोड्यूसर्स संस्था का गठन कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इंपा का अस्तित्व अपने पूरे रूप में वर्तमान रहा।

इंपा ने पिछले दिनों स्वर्णजयंती समारोह का आयोजन किया तब एक तरफ तो उन्होंने बी०के० आदर्श जैसे घटिया श्रेणी की फिल्मों के निर्माताओं का सम्मान किया, लेकिन दूसरी तरफ जुबेदा (प्रथम सवाक फिल्म 'आलमआरा' (१९२७) की नायिका), मेहताब (प्रथम रंगीन फिल्म 'झांसी की रानी' की नायिका एवं सोहराब मोदी की पत्नी), १९३९ के जमाने की प्रख्यात एवं चर्चित अभिनेत्री माधुरी, सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास, जिन्होंने मुकेश को पहली बार 'पहली नजर' में 'दिल जलता है तो जलने दो' गवा कर पेश किया, पार्श्व गायिका राजकुमारी, निर्माता-निर्देशक विजय भट्ट, शोभना सम आदि तीन दर्जन फिल्मकारों को भूल गये जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। राज कपूर को किनारे की सीट पर बिठा दिया तो उन्होंने दुबारा इंपा के किसी भी समारोह में शामिल न होने की कसम खा ली।

इंपा के स्वर्ण जयंती वर्ष में इंपा अब उस टूटन के कगार पर है, जहां आकर बड़े-बड़े संगठन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। रामराज नाहटा और राजेश खन्ना गुट एक-दूसरे की जड़ें खोदने और एक दूसरे को बेनकाब करने की योजनाएं बना रहे हैं। अगर राजेश खन्ना गुट सफल नहीं हो सका, तो संभव है अपने गुट के निर्माताओं को तोड़कर एक और इंपा बना लें, क्योंकि उनके गुट के फिल्म निर्माता आर्थिक रूप से संपन्न हैं और इंपा के वर्तमान रवैये से असंतुष्ट।

—रवींद्र श्रीवास्तव

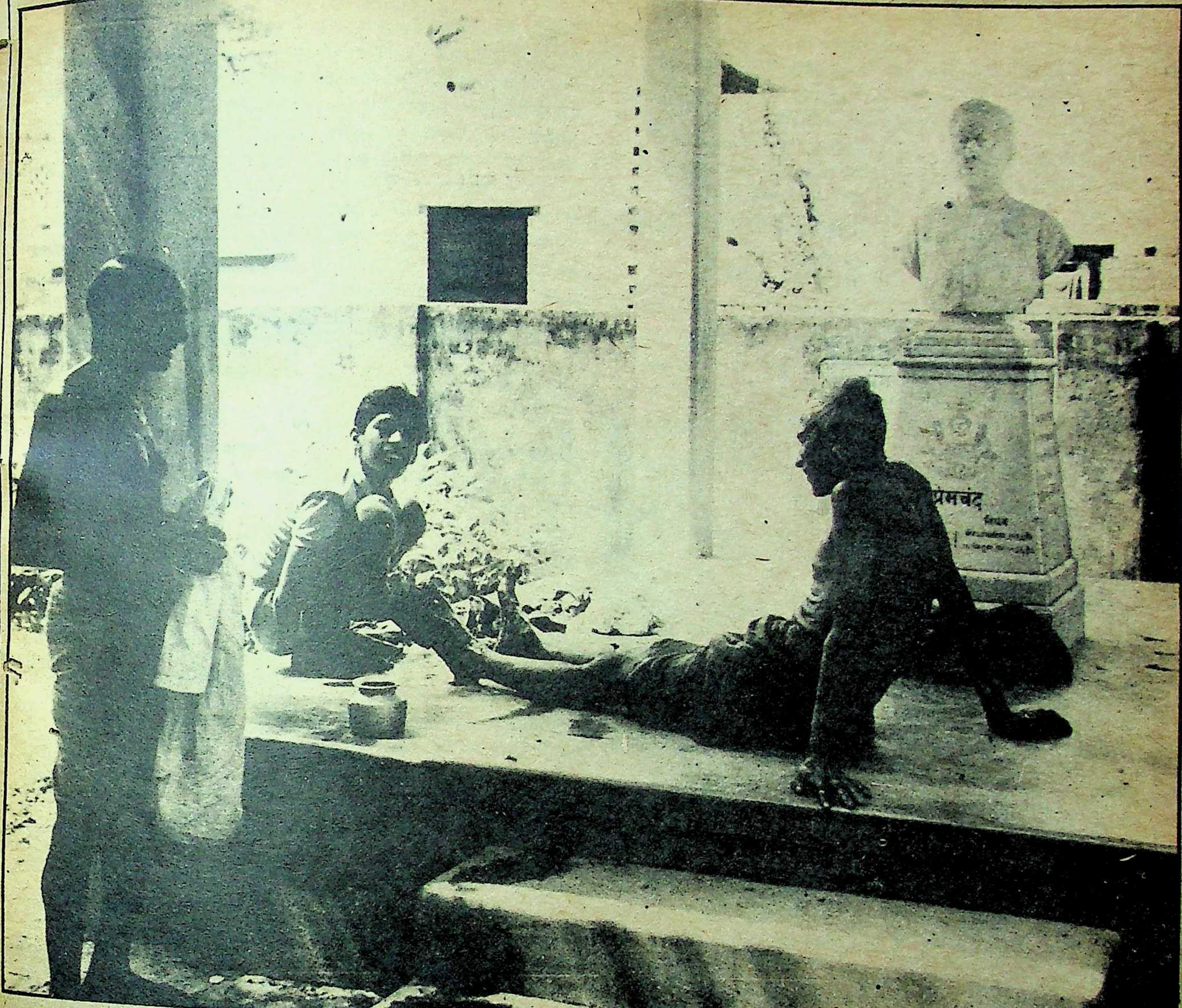

छाया : सुरेश्वर त्रिपाठी

यह व्यायामशाला नहीं और न स्नानघाट है। यह महान कथाकार प्रेमचंद का स्मारक है। वाराणसी से ५ किलोमीटर दूर, प्रेमचंद के जन्म स्थान लमही में स्वयं डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इसका ८ अक्तूबर, १९५९ को संगेबुनियाद रखा था। लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस समय उम्मीद जाहिर की थी यह स्मारक निश्चय ही राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप बनेगा। कभी पं० कमलापति त्रिपाठी ने भी कहा था कि यह स्मारक सारनाथ की ही भांति भव्य और रमणीक होगा। जिसके लिए उन्होंने झोली लेकर द्वार-द्वार जाकर धन संग्रह करने की भी बात की थी। जब १९८० में प्रेमचंद शताब्दी समारोह मनाया गया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अनेक भव्य घोषणाएं की थीं। लेकिन इस सबके बावजूद आज प्रेमचंद स्मारक की जो दशा है, वह आपके सामने है। यह 'लावारिस' स्थान साहित्यिक कार्यों के अलावा हर काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ३१ जुलाई को जब प्रेमचंद की जन्मतिथि मनायी जायेगी, तो शायद यहां साल में पहली बार झाड़-पोंछा लगेगा, फूल-मालाएं चढ़ायी जायेंगी और फिर साल भर के लिए इसे भुला दिया जायेगा। यों तो प्रेमचंद किसी स्मारक के मोहताज नहीं, लेकिन देश के इस महान कथाकार का कोई स्मारक बनाना ही है, तो खुदा के वास्ते ऐसा तो मत बनाइए !

शुशुनोवा

खेल की दुनिया विशेषकर जिमनास्टिक में एक नाम तेजी से उभरा है, सोवियत संघ की १८ वर्षीया येलेना शुशुनोवा का। अपने प्रतिभा-प्रदर्शन और खिताब जीतने के अभियान को जारी रखते हुए शुशुनोवा ने यूगोस्लाविया के जगरेब में चल रहे विश्व छात्र खेलों की जिमनास्टिक स्पर्धा के महिला वर्ग के सभी छह स्वर्ण पदक जीतकर न केवल जिमनास्ट जगत को ही स्तब्ध कर दिया, बल्कि वह इस सफलता से स्वयं भी स्तब्ध है। शुशुनोवा ने वाल्ट, अनइंवेनबार, बीम और फ्लोर के स्वर्ण जीतकर 'आल राउंडर' तथा 'टीम-खिताब' के स्वर्ण को भी अपनी झोली में डाल दिया।

वैसे तो शुशुनोवा अक्तूबर में स्टर्डम में होनेवाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी थी और अपने फार्म में भी नहीं थी-इसी बीच उसने जगबेर के विश्व छात्र खेलों की जिमनास्टिक स्पर्धा में भाग लेकर सनसनी फैला दी। जगबेर में उसके विजय-अभियान को देखकर जिमनास्ट जगत के लोगों की निगाहें स्टर्डम की ओर लगी हैं, यह देखने के लिए कि वहां शुशुनोवा क्या इसी तरह स्वर्ण पदक हासिल करेगी। उसकी तैयारी और प्रदर्शन को देखकर तो यही लगता है कि स्टर्डम में भी उसी का बोलबाला रहेगा।

सप्ताह में छह दिन चार-चार घंटे तक अभ्यास करनेवाली शुशुनोवा कहती है, "उसका पहला प्यार जिमनास्टिक है। और कामों के लिए उसके पास समय नहीं है।"

आमिर सुभानी

आमिर माने हाकिम यानी शासक। अपने नाम को चरितार्थ किया है, २३ वर्षीय आमिर

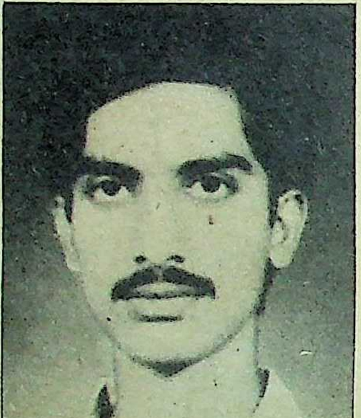

सुभानी ने, जिसने १९८६ की आई०ए०एस० परीक्षा में संपूर्ण भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार के सीवान जिले के बहुआरा गांव के एक सामान्य मुस्लिम परिवार में जन्मे आमिर प्रारंभिक शिक्षा से ही मेधावी छात्र रहे हैं। आई०ए०एस०, बी०ए० और एम०ए० की परीक्षाओं में भी आमिर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आमिर इंडियन स्टेटिस्टीकल रिसोर्सेज और बैंक की परीक्षाओं में भी प्रथम आये। आमिर की प्रतिभा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आमिर की मेहनत और लगन देखकर मां सरस्वती भी उनके साथ हैं, तभी तो जिस भी परीक्षा में वह बैठे अव्वल आते रहे।

आमिर ने आई०ए०एस० की तैयारी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, घर पर ही की। परिवार में तीन भाई और तीन बहनों में सबसे बड़े आमिर का सपना था कि वह आई०ए०एस० अफसर बनें। इसके लिए उन्होंने मेहनत की, नतीजा रहा कि वह चुने ही नहीं गये, बल्कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके, जहां उन्होंने अपने और परिवार के नाम, को रोशन किया, वहीं बिहार को भी यह सम्मान दिया कि उनके राज्य का एक व्यक्ति भारत में नंबर एक है। शालीनता और सादगी-पसंद आमिर अपनी निजी पहचान बनाना चाहते हैं, तभी तो उनकी इच्छा है कि वह भारत के एक आदर्श प्रशासक और नागरिक साबित हों। उनका कहना है कि उनके अंदर जो नैतिक मूल्य हैं, वे काफी गहरे और दृढ़ हैं और इसका हर समय वह ख्याल रखते हैं। आमिर को विश्वास है कि वह जिस पद पर भी रहेंगे अपने नैतिक मूल्यों की हिफाजत करेंगे। उनका मानना है कि अध्ययन, गुण, ग्राहकता और चुनौती पैदा करने की प्रवृत्ति जिस किसी भी व्यक्ति में होगी, वह सारी बाधाओं, अभावों को पार करके सफलता की ऊंचाई तक पहुंच ही जायेगा। आमिर वर्तमान में खगड़िया स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में प्रोबेशन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

ब्रैडमैन

क्रिकेट में जब रिकार्ड बनानेवालों का नाम आता है, तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन शीर्ष पर होते हैं। ५२ टेस्ट मैचों में २९ शतक और ९९.९४ की औसत से, ६,९९६ रन बनानेवाले ब्रैडमैन क्रिकेट के 'भीष्म पितामह' के रूप में भी जाने जाते हैं। ब्रैडमैन इन दिनों इसलिए चर्चा में हैं कि वह ४० वर्षों की खामोशी तोड़कर अपने निजी जीवन एवं अनुभवों की कहानी आस्ट्रेलियाई ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के जरिये लोगों को बतायेंगे। ए०बी०सी० ने यह शृंखला तैयार की है, जिसमें एक-एक घंटे के सात कार्यक्रम हैं। इसका प्रसारण क्रिसमस और नये साल की शुरुआत पर किया जायेगा।

७८ वर्षीय सर डोनाल्ड ब्रैडमैन १९४८ में क्रिकेट को अलविदा करने के बाद हर तरह के साक्षात्कार से अपने आपको बचाते रहे। क्रिकेटर, ब्रैडमैन के बारे में उन्हीं की जबानी सुनना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीकी ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा प्रसारित भूतपूर्व खिलाड़ियों के अनुभव सुनकर उन्होंने अब क्रिकेट छोड़ने के ४० वर्षों बाद निर्णय लिया कि वह भी अपने निजी जीवन एवं अनुभवों को लोगों तक पहुंचायेंगे।

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट के युग पुरुष ब्रैडमैन का कहना है कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि अनुभव लिखने का मतलब है—यह पहचान लेना कि मृत्यु अब समीप है। जिंदगी के जिस मुकाम पर मैं पहुंच गया हूं—वहां आकर लगा कि अब मुझे अपनी जिंदगी की किताब सबके सामने खोल देनी चाहिए।

ब्रैडमैन कहते हैं कि जो लोग मेरे जीवन एवं अनुभव से सनसनीखेज़ बातें सुनने की उम्मीद लगाये हुए हैं, उन्हें निराश होना

पड़ेगा, क्योंकि मैंने 'ड्रेसिंगरूम' के रहस्यों को उजागर न करने का इरादा किया है। सुंदरियों के साथ होटलों में होनेवाली मुलाकातें तथा नशाखोरी की आदतों के बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 'ब्रैडमैन की आपबीती' शृंखला में ब्रैडमैन ने अपने बचपन से लेकर अब तक के जीवन की खट्टी-मीठी यादों को ही शब्द दिया है। क्रिकेट के इस युगपुरुष से यह अपेक्षा भी रखनी चाहिए कि वह वे सब कुछ बतायेंगे, जिससे नयी पीढ़ी को कुछ सीखने को मिलेगा।

– दिनेश दीनू

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

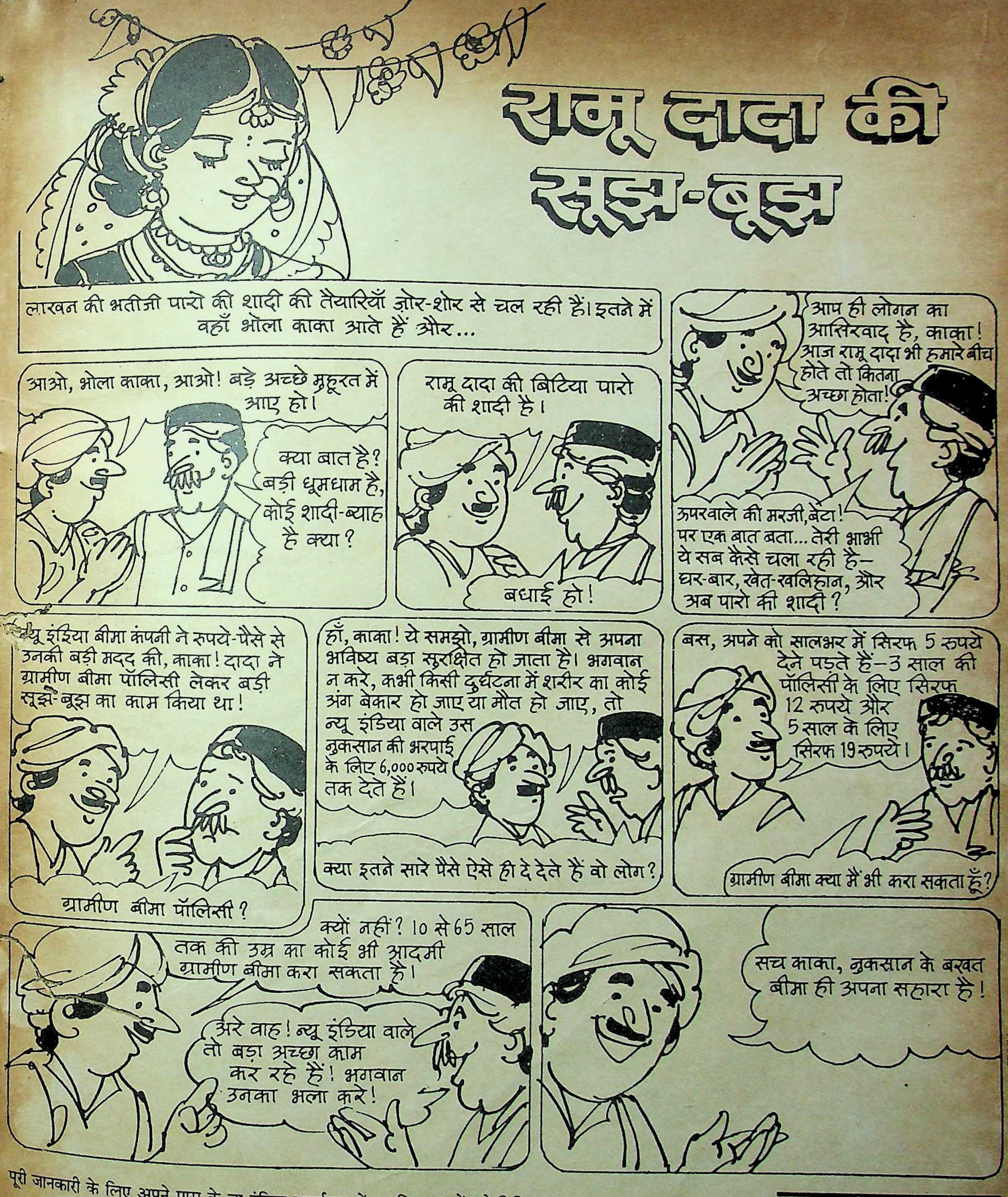
रामू दादा की सूझ-बूझ
लाखन की भतीजी पारो की शादी की तैयारियाँ ज़ोर-शोर से चल रही हैं। इतने में वहाँ भोला काका आते हैं और...
आओ, भोला काका, आओ! बड़े अच्छे मुहूरत में आए हो।
क्या बात है? बड़ी धूमधाम है, कोई शादी-ब्याह है क्या?
रामू दादा की बिटिया पारो की शादी है।
बधाई हो!
आप ही लोगन का आसिरवाद है, काका! आज रामू दादा भी हमारे बीच होते तो कितना अच्छा होता!
ऊपरवाले की मरजी, बेटा! पर एक बात बता... तेरी भाभी ये सब कैसे चला रही है— घर-बार, खेत-खलिहान, और अब पारो की शादी?
न्यू इंडिया बीमा कंपनी ने रुपये-पैसे से उनकी बड़ी मदद की, काका! दादा ने ग्रामीण बीमा पॉलिसी लेकर बड़ी सूझ-बूझ का काम किया था!
ग्रामीण बीमा पॉलिसी?
हाँ, काका! ये समझो, ग्रामीण बीमा से अपना भविष्य बड़ा सुरक्षित हो जाता है। भगवान न करे, कभी किसी दुर्घटना में शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए या मौत हो जाए, तो न्यू इंडिया वाले उस नुकसान की भरपाई के लिए 6,000 रुपये तक देते हैं।
क्या इतने सारे पैसे ऐसे ही दे देते हैं वो लोग?
बस, अपने को सालभर में सिरफ 5 रुपये देने पड़ते हैं—3 साल की पॉलिसी के लिए सिरफ 12 रुपये और 5 साल के लिए सिरफ 19 रुपये।
ग्रामीण बीमा क्या मैं भी करा सकता हूँ?
क्यों नहीं? 10 से 65 साल तक की उम्र का कोई भी आदमी ग्रामीण बीमा करा सकता है।
अरे वाह! न्यू इंडिया वाले तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं! भगवान उनका भला करे!
सच काका, नुकसान के बखत बीमा ही अपना सहारा है!

R K SWAMY/NIA/2977/HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इंडिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

बीमा — नुकसान में आपका सहारा!

न्यू इंडिया एश्योरेंस

(जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की एक सहायक कं

कावासाकी-बजाज के बी 100.
इस पर सवार होकर आप बाज़ार भी जा सकते हैं.

bajaj auto

Value for mone
for years

कावासाकी-बजाज के बी १००.

सबसे मज़बूत, सबसे तेज़-तर्रार, सबसे सुरक्षित मोटरसाइकल. भारतीय सड़कों के लिए कारगर ढंग से ढाली गयी जापानी टेक्नालॉजी.

आपके लिए के बी १०० पेश कर रहे हैं भारत की सबसे जानी-मानी टू और थ्री-व्हीलर कंपनी बजाज और उच्च जापानी टेक्नालॉजी में महारत हासिल कंपनी— कावासाकी, वह कंपनी जिसने दुनिया की सबसे तेज़ रफ़्तार वाली मोटरसाइकल का निर्माण कर एक नया इतिहास रचा है.

के बी १०० के साथ आप पाएंगे देश-भर में फैली बजाज की सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स डीलरों की जानी-मानी सेवा सुविधाएं. और हर सेवा केंद्र में मौजूद हैं कारखाने में ख़ास तौर पर प्रशिक्षित मैकेनिक ताकि आपकी मोटरसाइकल हरदम शानदार स्थिति में बनी रहे.

कावासाकी-बजाज के बी १०० की सवारी कीजिए. आप खुद ही समझ जाएंगे कि हर दौड़ में क्यों है बेजोड़-— बजाज!

bajaj group

LINTAS BAJ 59 2822 HI

इंजीनियरिंग में ऐसा दम, हर मुश्किल इसके लिए कम.

कावासाकी-बजा

डायमंड पाकेट बुक्स में

राजहंस

का नया सामाजिक उपन्यास

नासूर

समाज में रिसते नासूर की हृदय विदारक कहानी

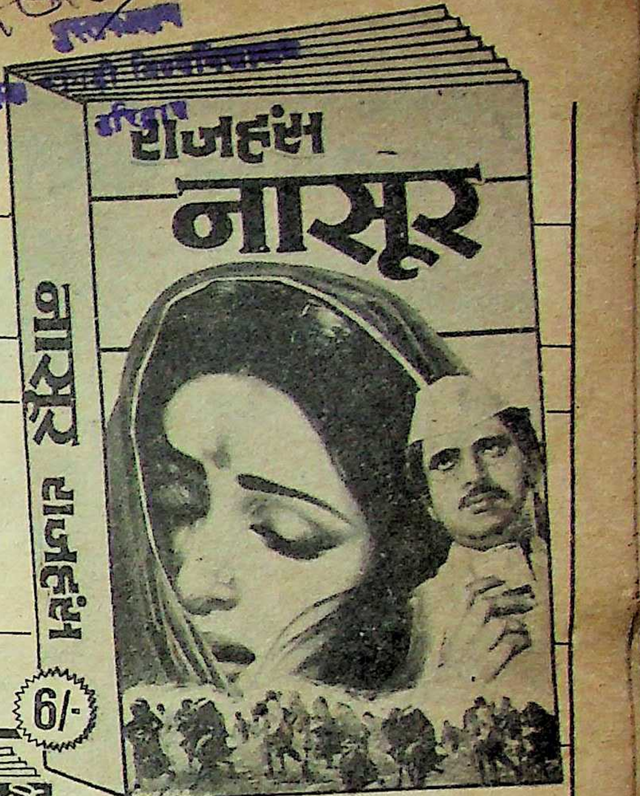
राजहंस
नासूर
नासूर राजहंस
6/-

बेटी का हत्यारा
राहुल

सस्पेंस थ्रिल और एक्शन से भरपूर

राहुल का नया उपन्यास

बेटी का हत्यारा

6/-

लोकदर्शी
अंधी प्रतीक्षा
6

लोकदर्शी

का नया उपन्यास

अंधी प्रतीक्षा

6/-

जेम्स हेडली चेईज़
diamond
बेगम और इक्का

जेम्स हेडली चेईज़

का नया जासूसी उपन्यास

बेगम और इक्का

6/-

वेद प्रकाश काम्बोज
उस रात का अपराधी
6

वेद प्रकाश काम्बोज

का नया जासूसी उपन्यास

उस रात का अपराधी

6/-

सुरेन्द्र मोहन पाठक
diamond
रेड सर्किल सोसायटी

सुरेन्द्र मोहन पाठक

का 'सुनील सीरीज' का एक और जासूसी उपन्यास

रेड सर्किल सोसायटी

6/-

Mediamind

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि. 2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

घमौरियों से आराम के लिए टाल्कम पाउडर नहीं, नायसिल चाहिए.

नायसिल लगाइए.
घमौरियों से जल्द आराम पाइए.
Glaxo
To open, twist and pull cap.
Glaxo
nycil®
PRICKLY HEAT POWDER
200 gms net
HTB-GLL/8808

नायसिल एक औषधियुक्त पाउडर है. घमौरियों की हर परेशानी से फौरन आराम दिलाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया. खुजली, जलन और चुनचुनाहट से तुरंत आराम दिलाता है और घमौरियों को फैलने व बढ़ने से रोकता है, जो टाल्कम पाउडर से संभव नहीं.

नायसिल—घमौरियों से आराम पाने का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद उपाय.

1. अत्यधिक पसीने को रोकता है.
2. पसीने को सोखता है.
3. बदबू पैदा करनेवाले कीटाणुओं का नाश करता है.
4. त्वचा को आराम पहुँचाता है.

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक १६

माया

३१ अगस्त, १९८७

माया
राजीव क्या संकट से उबर पायेंगे?

१४

यह अंक

आवरण कथा

राजीव गांधी के राजनीतिक अस्तित्व पर घोर संकट घिरा है। इस संकट से उबरने के लिए उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया है। लेकिन क्या वह अपनी दरकती विश्वसनीयता और चरमराते नेतृत्व का सफल जीर्णोद्धार कर पायेंगे?

वी०पी० सिंह और विपक्ष

राजा मांडा के कांग्रेस से बाहर आने के बाद विपक्ष और उनके रिश्ते क्या शक्ल ले रहे हैं? २२

मध्य प्रदेश

दल से निष्कासित होने के बाद विद्याचरण शुक्ल का अपना जनाधार तलाशने का मध्य प्रदेश दौरा सफल रहा या विफल? ६६

बिहार

क्या बिहार के ७० प्रतिशत विधायकों को जन-गण-मन तक याद नहीं? एक नायाब सर्वेक्षण। ५४

श्रीलंका भारत समझौता

यह अभूतपूर्व समझौता कैसे संपन्न हो सका और क्या यह सफल हो पायेगा? साथ में राजीव गांधी पर हुए कातिलाना हमले की रिपोर्ट ३२

मेरठ दंगे

पिछले चार महीने से मेरठ में सांप्रदायिकता की आग को सुलगाये रखने वाले मूल कारण कौन से हैं? ३६

राजस्थान

मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी में ऐसी कौन सी खासियत है कि वह अपनी डगमगाती नैया को फिर से किनारे पर लगा लेते हैं? ६०

दिल्ली दरबार: मित्रमंडली स्वाहा! ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
फोटोफीचर ९
देश: संसद में बोफोर्स २०
देश: चंद्रशेखर का साक्षात्कार २६
प्रसंगवश: मुजफ्फरनगर में राजा मांडा २८
उ०प्र०: वीर बहादुर सिंह का पुनर्जीवन ४०
उ०प्र०: विधायकों के ठाट ४३
महाराष्ट्र: विधानसभा अध्यक्ष पर 'अविश्वास' ४६
गुजरात: सांप्रदायिकता के बीज किसने बोये? ४९
बिहार: सरकारी संत संकट में ५२
बिहार: एम०एल०ए० नंबर ३२५ ५८
व्यक्तित्व: विजयराजे सिंधिया दोराहे पर ७२
विवाद: नेहरू शताब्दी-समारोह में नेहरू की खोज ७६
राडार: इलाहाबाद में राजीव को वीर बहादुर का नजराना ७९
अर्थतंत्र: जब व्यवसायी आपस में लड़ते हैं ८२
परदे के पीछे ८६
फिल्म: वापसी के बाद विनोद खन्ना ८८
संस्मरण: सलीमअली का पक्षियों से आत्मिक रिश्ता था ९१
अचानक ९५
लोग ९६

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
विशेष संवाददाता
दिल्ली: राहुल देव
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
दिल्ली: पुनीत टंडन
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक:
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शंतनु मुखर्जी
सज्जा:
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

मनोरमा

३१ अगस्त '८७

आवरण कथा

क्या स्त्री-पुरुष के बीच प्लैटोनिक लव संभव है ?

प्लैटोनिक लव या अफलातूनी मोहब्बत वास्तव में एक सुंदर भावना का नाम है, जिसकी गहराई बिना समझे प्राय: लोग छींटाकशी का विषय बना लेते हैं। क्या ऐसा प्रेम यथार्थ जीवन में संभव है ? कौन अधिक चाहता है यह संबंध बनाना-स्त्री या पुरुष ?

प्रमुख आकर्षण

हमसफर • रोरिक एवं देविका रानी : कला को समर्पित युगल
फीचर • मैं जीवित हूँ मां
हवा कुंवारी है • कितने खूबसूरत होते हैं कालेज के दिन
मेरी सुहागरात • उस रात हम खूब रोये
मेकअप • लाइट मेकअप यानी श्रृंगार भीना-भीना
व्यक्तित्व • मंजरी जोशी : सीधा-सरल किन्तु लुभावना व्यक्तित्व
कैरियर • टेलीफोन आपरेटर
व्यंजन • फिर वही लौकी-कद्दू…
फैशन • इस मौसम के फैशन रंग-रंगीले

अन्य आकर्षण

• बच्चे क्यों बहकते हैं ? • थ्री पीस ड्रेस
• फूलों भरा गुलदस्ता • नया रूप नया निखार
• अदालती शादी के चक्कर
• कुंवारियों को कैसा जीवन-साथी चाहिए ?

कथा साहित्य

हास्य-व्यंग्य : वह अनोखी जोड़ी/ शेखर जोशी
का पर करौं सिंगार/ विनोद
कब होगी भेंट ?/ मथुरा कलौनी
डोली/ सीमा मेहरोत्रा

साथ ही सभी नियमित स्तंभों में चुनी हुई रचनाएं।

१५ अगस्त '८७ तक प्रकाश्य • मूल्य ५ रु०

चिट्ठियां

माया
राजा की
राजीव को खुली
चुनौती

सुपर स्टार का इस्तीफा

माया' १५ अगस्त, १९८७ अंक में प्रकाशित विशेष रिपोर्ट—'अमिताभ बच्चन : इस्तीफा क्यों देना पड़ा' पढ़कर सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी मालूम हुई। साथ ही राम जेठमलानी द्वारा प्राप्त दस्तावेज से यह बात जाहिर हो चुकी है कि अजिताभ बच्चन ने स्विट्जरलैंड में ८५ लाख रुपए का मकान खरीदा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो दस्तावेज राम जेठमलानी ने प्राप्त किया और जिसे 'इंडियन एक्सप्रेस' में छापा गया, उसे केंद्र सरकार क्यों नहीं प्राप्त कर सकी ? निस्संदेह इसका दो में से एक ही कारण हो सकता है—या तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बच्चन बंधुओं पर अटल विश्वास था या फिर वह उनको बचाने में लगे थे। परंतु जब चेहरे से नकाब उठ गया, तो प्रधानमंत्री के पास अमिताभ बच्चन को इस्तीफा देने के लिए कहने के अलावा कोई अन्य उपाय न था। —सुरेंद्र कुमार शर्मा, भुईधारा, धुरलख, समस्तीपुर (बिहार)।

धर्म के नाम पर धोखा

माया' १५ अगस्त के अंक में नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में हरिजनों के सामूहिक प्रवेश के मामले की संपूर्ण रपट 'भगवान के घर में राजनीतिक प्रदूषण' पढ़कर यह महसूस हुआ कि वर्तमान में धर्म के परिवेश में जो भी कुछ चल रहा है, वह धर्म न होकर एक दंभ व छलना मात्र है।

चूंकि, हमारी मानसिकता धर्म भीरु है, अत: धर्म के नाम पर अपनी फसल पैदा करनेवाले राजनेता आज भारतीय जनजीवन के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के विवाद उत्पन्न कराकर धर्म-प्रेमी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कहां तक उचित है ? ऐसे ही विवादों व समस्याओं से आज धर्म का रूप विकृत हो गया है और धर्म के वास्तविक रूप से हम

विभिन्न सैलों में नियुक्तियों की जांच हो

माया' ३१ जुलाई, '८७ के अंक में 'युवा इंका में उठा-पटक' लेख उन सभी कांग्रेसजनों की दबी भावनाओं को उजागर करता है जो आज की दयनीय स्थिति में भी पार्टी के लिए समर्पित हैं। अराजकता, चाटुकारिता और अपने काले धन के बल पर जातिवाद का व्यूह रचकर कांग्रेस में ऐसे तत्वों का वर्चस्व हो गया है, जिनकी कांग्रेस या लोकतंत्र में तनिक भी आस्था नहीं है। ये लोग जनता की सेवा और जन-कल्याण से दूर भ्रष्ट अधिकारियों के निकट अधिक हैं। लेखक ने 'आरोप' उपशीर्षक से उन सभी तथ्यों का भंडाफोड़ किया है जो कांग्रेस की जड़ में दीमक की तरह लगे हैं।

वास्तव में विभिन्न सैलों का गठन करके उनमें ऐसे अवसरवादी पंचतंत्र की कथावाले 'बंदरों' का मनोनयन किया गया है जो पार्टी की जड़ों को खोखला करने के साथ-ही-साथ अपने स्वामी के मुंह पर बैठी मक्खी का वध नंगी तलवार से करने पर तुले हुए हैं। इन तथाकथित युवा-तुर्कों की देश और विदेश में भारत और पार्टी की छवि धूमिल करने में विशेष भूमिका रही है। मास्को 'यूथ फैस्टिवल' पर लिखी गयी रिपोर्ट की स्याही अभी सूखी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार को आयोग बैठाकर तथ्यों की जानकारी करने की आदत पड़ गयी है। मेरा सुझाव है कि पार्टी को कब्र में जाने से बचाने के लिए तथा युवाओं की बेलगाम हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए चार बड़े इंकाइयों सर्वश्री कमलापति त्रिपाठी, सरदार स्वर्ण सिंह, सी० सुब्रमण्यम और सादिक अली ने राजनीतिक हिंसा को कोसते हुए जो अपील की है, यदि समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो पार्टी की भ्रष्टाचारी सेना इसके त्यागमय उज्ज्वल इतिहास पर कालिख पोतकर ही सांस लेगी। —बाबूराम शर्मा, पूर्व सभासद , नगरपालिका खतौली, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। —मनोज पुष्प प्रजापति, सचिव : पत्र लेखक मंच, शामगढ़ (मंदसौर)।

हरिजन खेत का बैल नहीं

भगवान के घर में राजनीतिक प्रदूषण' ('माया' अगस्त प्रथम पक्ष) की रिपोर्ट पढ़ी। राजस्थान के श्रीनाथ जी के मंदिर में हिंदू धर्म के ठेकेदारों द्वारा हरिजनों को प्रवेश करने से रोका गया, तो इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदार हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हैं। धर्म की आड़ में राजनीति करनेवाले लोग हरिजनों को खेत का बैल न समझें, नहीं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत को आज़ाद होने में समय लगा। शर्म तो उन हरिजन नेताओं को आनी चाहिए जो हरिजनों को श्रीनाथ जी दर्शन हेतु ले गये। इन हरिजन सांसदों तथा विधायकों को मंदिर का बहिष्कार करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं, जब भारत में जातिवाद की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगी और हिंदू धर्म एक बार फिर खतरे के कगार पर खड़ा होगा। —विजय कुमार आनंद, अध्यक्ष, अखिल भारतीय युवा दलित पैंथर, बंबई

आवरण कथा की त्रिमूर्ति

यह त्रिमूर्ति भविष्य में जरूर कुछ नया गुल खिलायेगी, क्योंकि इन्हें कुरसी की चाहत तिल भर की नही है, इस बात की पुष्टि इनके कार्यों-वक्तव्यों से कई बार हो चुकी है। वी० पी० सिंह को जनता का अंधा-समर्थन मिलना संभव है, वहीं आरिफ मोहम्मद खां सिद्धांतों की खातिर प्रगतिशील विचारधारा के लोगों के पथ-प्रदर्शक बन चुके हैं। अरुण नेहरू राजनीतिक पैंतरेबाजी के शहंशाह हैं। —मनोज अरुण व्यास, व्यास गली, बडनगर, म०प्र०।

श्री सिंह की असंदिग्ध ईमानदारी और कार्य-कुशलता तथा श्री खान का प्रखर सांप्रदायिकता विरोध राजीव को सहा नहीं हुआ। वास्तव में नेहरू खानदान की जायदाद कांग्रेस-इ में ईमानदार और स्वाभिमानी लोग रह ही नहीं सकते। वहां तो बेईमानों और चाटुकारों की ही पूछ है। —रामतीर्थ, कोट बाजार, सीतामढ़ी, बिहार।

वास्तव में जुलाई द्वितीय अंक की आवरण कथा 'त्रिमूर्ति क्या गुल खिलायेगी' से पूरा देश शायद यह जान चुका होगा कि बोफोर्स की आड़ में वी० पी० सिंह, अरुण-नेहरू, व आरिफ ने कुरसी के मायाजाल में पार्टी व राजीव गांधी से धोखा किया है, अगर वी०पी० सिंह में दम है, तो पहले सबूत पेश करते। यह राजीवजी की मेहरबानी ही समझनी चाहिए कि अपने पूरे मंत्रियों के अलावा खासतौर से वी०पी० सिंह को महत्व दिया, उसी का नुकसान शायद अब राजीव साहब को भुगतना पड़ रहा है।—अणदाराम झाला, साजती गेट, बिलाड़ा।

कामयाबी संदिग्ध

वी० पी० सिंह की ईमानदार छवि, अरुण नेहरू की चतुराई भरी सियासती चालें साथ में आरिफ मोहम्मद खां की सिद्धांतवादिता सब कुछ तो है, इन असंतुष्टों के पास, फिर भी ये अपने मकसद में कामयाब होंगे ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय राजनीति में नैतिकता, निर्भीकता तथा ईमानदारी का अभाव है। कांग्रेस ज्यादातर ऐसे नेताओं की ऐसी जमात है जो अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकती। यही वजह है कि वी०पी० सिंह और उनका गुट धमाका तो कर सकता है, लेकिन उसकी गूंज ऐसी नहीं होगी जो कांग्रेस रूपी इमारत को ढहा सके। —चौधरी बशदेव सिंह, पूर्वी बाजार, मुगलसराय, वाराणसी।

खंडन

माया' के ३१ जुलाई के अंक में खोजखबर स्तंभ के अंतर्गत 'युवा इंका में उठा पटक' में मेरे संबंध में जो टिप्पणी की गयी है, वह नितांत असत्य, भ्रामक तथा तथ्यहीन है। आगरा शहर युवा इंका के अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति का कारण व्यापारियों से चंदा उगाही नहीं है, जैसाकि श्री जोशी ने लिखा है। मेरी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संतोष सिंह ने योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की है। मैं गत पंद्रह वर्ष से युवा इंका में हूं तथा वार्ड-उपाध्यक्ष, शहर संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री, महामंत्री तथा उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के बाद ही मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। —राधेश्याम गुप्ता, अध्यक्ष, शहर युवक कांग्रेस-इ आगरा

खयालात

डा० जगन्नाथ मिश्र

ज्ञानी जैल सिंह

बेनजीर

यदि सिंहलियों ने हमला किया, तो मेरा गुट फिर हथियार उठाने से नहीं चूकेगा।**—वी० प्रभाकरण, लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम**

मैं केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ़ ही नहीं, देश के गद्दारों के खिलाफ भी लड़ रहा हूं।**—वी०पी० सिंह बड़ोदरा की सभा में**

भाड़े की बसें और किराये की भीड़ कांग्रेस-इ को जिंदा और गतिशील नहीं रख सकती। ये (चीजें) केवल उनमें फैले आतंक की प्रतीक हैं जो उनके अपने ही कर्मों से जनमा है । **—रामधन कांग्रेस-इ सांसद**

इंका का बेड़ा गर्क होने से बच सकता है, बशर्ते कि संगठन का लोकतंत्रीकरण किया जाये और भिन्न-भिन्न स्तरों पर विवेक से काम करने की छूट दी जाये। **—डा० जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार**

राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह कभी महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण नहीं बन सकते हैं। वे पाखंडी हैं, और गरीबों के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं। ...गांधी की मुद्रा में फोटो खिचवाने या छपवाने से कोई गांधी नहीं हो जाता। **—कांग्रेस-इ कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी**

मैंने कहा था कि राष्ट्रपति की कुरसी से हटने के बाद मैं कुछ बोलूंगा। मगर क्या बोलूं ? जहां सिर्फ बातें ही बातें हों (और काम नहीं) वहां कुछ कहने की क्या जरूरत ? **—भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह**

भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने यदि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी, तो इसका यह मतलब नहीं कि इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गये हैं। **—प्रसिद्ध विधिवेत्ता राम जेठमलानी**

मैं राजनीति में दिलचस्पी रखनेवाला पति नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मेरा पति ऐसा हो, जिसकी अपनी रुचियां और अपना कैरियर हो। **—कु० बेनजीर भुट्टो**

मैं फिल्म उद्योग को एक 'मंदिर' कहता हूं, जहां लोग रोज आते हैं और हंडों में रुपये डालते हैं। हम लोग इस उद्योग के पंडे हैं, हमारा अस्तित्व उन्हीं पूंजी लगानेवालों की वजह से बना हुआ है। **—'सड़कछाप' फिल्म के निर्माता अनिल गांगुली**

क्षेत्रीय स्वायत्तता इसके सिवा कुछ नहीं कि यह अलगाववाद का पहला कदम है। इसकी तो चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। **—गृहमंत्री बूटा सिंह**

कोई भी देश यहां तक कि रूस भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। **—रामकृष्ण हेगड़े**

मैं समझता हूं, मैं विवादास्पद होने के लिए ही पैदा हुआ हूं। **—अमिताभ बच्चन, संडे मेल**

मित्रमंडली स्वाहा !

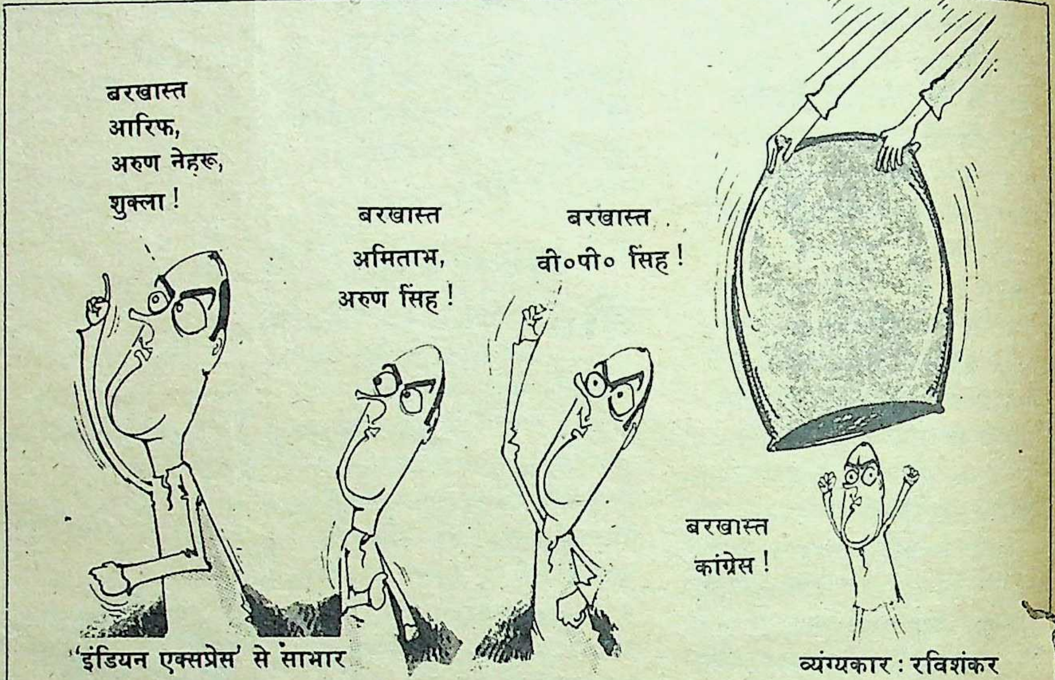

'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार

व्यंग्यकार : रविशंकर

चाणक्यीय अंदाज में जब बघेल ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपना दर्शन बघारते हुए कहा कि दिल्ली दरबार अब और कितने दिनों तक बैसाखी पर अपना नेतृत्व ढोयेगा, उसे अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, तो यह सुनकर माखन लाल फोतेदार आग बबूला हो उठे। अंगुलियों में फंसा सिगरेट का टुर्रा जूते की टो के हवाले करते हुए बघेल ठाकुर की तरफ लपके, लेकिन दूरी ज्यादा थी। वह खिसियायी बिल्ली की तरह मात्र गुर्रा कर ही रह गये। अगर वह अर्जुन सिंह की तरफ पूरी तरह लपक जाते, तो उनके कंधे पर कथित लदा दिल्ली दरबार बकौल उनके धड़ाम से नीचे गिर जाता। वह अकेले सतीश शर्मा पर दिल्ली दरबार का बोझ छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वह दिल्ली दरबार की राजनीतिक बैसाखी के सुख से वंचित नहीं होना चाहते थे। यों तो दिल्ली दरबार की रीढ़ की हड्डी गोपी अरोड़ा और सरला ग्रेवाल संभाले हुए थे। लेकिन बैल गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की नानी द्वारा सुनायी गयी कहानी फोतेदार जी के चैतन्य मन पर पूरी तरह छायी हुई थी। वह दांत किटकिटा कर बोले—"बघेल ठाकुर, मेरे कंधों पर दिल्ली दरबार का समूचा बोझ अगर न लदा होता, तो आज मैं तुझे नानी याद दिला देता।"

दिल्ली दरबार के संसदीय कोश में पिछले दिनों काफी इजाफा हो चुका है। कुत्ता, नानी याद दिला दूंगा आदि-अनादि शिष्ट संसदीय भाषा की परिधि में ही नहीं आ चुके हैं, बल्कि सम्मान सूचक उद्बोधन हो चुके हैं। जैसे ही जार्ज के इनर सर्किट दूरदर्शन पर (इस पर अजित पांजा का कब्जा नहीं है) दरबारियों ने देखा-सुना कि बघेल ठाकुर दिल्ली दरबार को बैसाखी मुक्त होने का प्रवचन दे रहा है, तो वे लाल-पीले होकर दनदनाते दरबार में घुस आये। समदर्शी एच०के०एल० भगत गुस्से में कांपते हुए, हाथ कमर पर रखकर अर्जुन सिंह के सामने तन कर खड़े हो गये—"तुम यह मत समझना कि मैं बहुत नाटा हूं। इतना कद तो मेरा है ही कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। जंगली मध्य प्रदेशीय, पहले तो मेरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब फिर से दिल्ली दरबार पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है। तुझे तो मैं तेरी नानी याद दिला दूंगा। एक बार २४, अकबर रोड पर क्या कब्जा कर लिया था, तू समझता है कि तू बहुत बड़ा तुर्रम खां है। तुझे नहीं मालूम कि दिल्ली दरबार का राजनीतिक स्वास्थ्य कितना खराब है? तू तो चाहता है कि बैसाखी खींच ली जाये और दिल्ली दरबार धड़ाम से गिर पड़े। मुझे सब मालूम है कि तू वी०पी० सिंह से मिला हुआ है और ठाकुरवाद चला रहा है। लेकिन हम लोग तेरी एक नहीं चलने देंगे। तू अपने बाप का नहीं हुआ, तो इस पिता तुल्य दिल्ली दरबार का क्या होगा!"

बघेल ठाकुर गुरु-गंभीर मुद्रा में खड़े अपनी मोटी कमानी के चश्में का लैंस रूमाल से पोंछते रहे। गुस्से में बदहाल भगतजी के मुंह से जब झाग निकलने लगा, तो चश्में को चेहरे के हवाले करते हुए अर्जुन सिंह ने भगतजी को अपने आगे से धकिया दिया—"राजनीति में चमचों की निश्चित भूमिका होती है। मैं भी चमचा हूं। राजतंत्र बिना चमचों के कतई नहीं चल सकता है। वी०पी० सिंह भी कभी दिल्ली दरबार के चमचे हुआ करते थे। आज वह चमचों को भ्रष्टाचारी कह कर उनके खिलाफ पूरे मुल्क में अभियान चलाये हुए हैं। अवाम उनकी बात सुन रहा है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वी०पी० सिंह की तरफ से अवाम का ध्यान हटाकर दिल्ली दरबार की तरफ उसको मुखातिब करें। चोर होना बुरी बात नहीं है। चोर समझा जाना खतरनाक होता है। हमको इस खतरे का मुकाबला करना होगा। वी०पी० सिंह क्या कोई भी खड़ा होकर हम लोगों की ऐसी-तैसी कर देगा।" सीताराम केसरी अपनी खास चाल में आगे बढ़कर बघेल ठाकुर पर कोई हल्ला बोलें कि उसके पहले चिलमन से झांकती दरबारिन ने इशारा किया। इशारा पाते ही पास खड़े पी०वी० नरसिम्हा राव ने तुरन्त आगे बढ़कर केसरीजी की धोती खींच दी। अर्जुन सिंह ने कनखियों से सब कुछ देखा और अपना प्रवचन आगे जारी रखा—"हमाम में सब नंगे होते हैं। वी०पी० सिंह भी हैं। राजनीति में हम सब एक दूसरे की नंगई को छिपाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इससे विरोधी दल अलग नहीं हैं। चूंकि हम समस्या को उसकी पूर्णता में नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि विरोधी दल हमारे शत्रु हैं। कतई नहीं, जिस तरह हम सब दिल्ली दरबार को बचाना चाहते हैं, उसी तरह विरोधी दल उसको बचाना चाहते हैं। हम सारे राजनीतिज्ञ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केवल हमारी दृष्टि भ्रमित है। अगर कोई हम राजनीतिज्ञों का दुश्मन है, तो ये वोटर। वोटर हम लोगों को लड़ा रहा है और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि लड़ रहे हैं। हमें इस संकट के समय में समझदारी से काम लेने की जरूरत है। व्यापक राजनीतिक समझदारी की पहली और अंतिम बुनियादी बात है निर्भय होना। अंदर से चाहे जितना आतंकित या भयभीत रहो, लेकिन ऊपर से निर्भीक होने का परफैक्ट ड्रामा होना चाहिए। यह संसार एक बड़ा रंगमंच है और हम लोग अभिनेता हैं।" अर्जुन की दर्शन की चाशनी चढ़ी चमत्कारी बात सुनकर दरबार में पीछे खड़े मूक समर्थकों ने अचानक तालियां पीट दीं। दिल्ली दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से रोमांचित हो उठा।

जब मूक समर्थकों की तालियों की गड़गड़ाहट कुछ मिनटों तक बंद होने को नहीं आयी, तो फोतेदार अपने स्थान पर खड़े-खड़े थानेदार की तरह बरसे—"यह क्या मजाक हो रहा है। यह दिल्ली दरबार है या कोई नौटंकी। बंद करो तालियां, नहीं तो लाठी चार्ज करवा दूंगा।" केसरीजी फिर लपके। जब तालियों की गड़गड़ाहट पर उनका कोई बस

नहीं चला, तो वह बूटा सिंह पर बरस पड़े—“बूटा यह तुम्हारा ला एंड आर्डर है। अरे दिल्ली को बचा नहीं पाते हो, तो कम-से-कम दिल्ली दरबार को तो बचा लो।” बूटा सिंह गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किये जा रहे थे। वह चिदम्बरम की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाये—“यह आन्तरिक सुरक्षा का मामला है। यह देखेगा।” इशारा पाते ही चिदम्बरम अपनी लुंगी संभालते हुए मूक समर्थकों पर आक्सफोर्डी अंग्रेजी में पिल पड़े—“बंद करो ये तालियां, नहीं तो आतंकवादी कानून का फंदा तुम लोगों के गले में डलवा दूंगा। दिल्ली दरबार में दशकों से तालियां केवल टेप से बजती आ रही हैं।

हमारे पास तालियों की गड़गड़ाहट और जयजयकार के सैकड़ों टेप हैं। जब तालियों की जरूरत होगी, दिल्ली दरबार का साउंड कन्ट्रोल रूम टेप बजा देगा। तुम लोगों की हमको जरूरत नहीं है। फौरन बंद करो ये तालियां, नहीं तो हम दिल्ली दरबार की सुरक्षा की आड़ में इमरजेंसी की उद्घोषणा करा देंगे... बंद करो तालियां पीटना... बंद करो।” चिदम्बरम की धमकी को किसी ने नहीं सुना और तालियां बजती रहीं। बूटा सिंह गुरु ग्रंथ साहब का जाप करने के बाद उठे और अर्जुन सिंह की तरफ लपके—“अरे बघेल ठाकुर! मुझे तेरे मनसूबों का पूरा पता है। तेरी नजर मेरी होम मिनिस्टरी पर है। जब तेरा कहीं बस नहीं चला, तो अब दिल्ली दरबार में ला एंड आर्डर की प्राबलम पैदा कर रहा है। तूने मेरी पुलिस के सारे टेलीफोन डेड करा दिये हैं, ताकि आतंकवादियों के दिल्ली आने की सूचना न मिल पाये। क्या तू समझता है कि मेरे पास दिल्ली में आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी से पिंड छुड़ाने के लिए कोई बहाना नहीं है। सबसे बड़ा बहाना, तो मैंने खोज ही निकाला है कि तूने मेरी पुलिस के फोन डेड करा दिये हैं, ताकि मुझे उनके आने की सूचना तुरन्त न मिल पाये।” अर्जुन सिंह ने फिर से अपनी मोटी कमानी का चश्मा चेहरे से उतार कर उसके लैंस की सफायी रूमाल से शुरू कर दी।

बम्बई के स्टूडियों में फिल्म की शूटिंग करते हुए जब अमिताभ बच्चन को पता चला कि दिल्ली दरबार को ‘बोल्ड एंगरी मैन’ की एक्टिंग करनी है, तो वह फौरन से पेशतर दिल्ली दरबार में आ गिरे। वह अपने साथ आधे दर्जन से ऊपर दिल्ली दरबार का मेकअप करने के लिए मेकअप मैन भी साथ ले आये। जब वह दिल्ली दरबार में गिरे, तो माहौल में भयंकर गरमी थी। दिल्ली दरबार सब कुछ टुकुर-टुकुर देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। गले में पड़ी तख्ती उलटी हो गयी थी। फोतेदार ने उसे सीधा कर दिया, जिस पर लिखा हुआ था—‘बोफोर्स की दलाली’। एक दूसरी तख्ती पर धूल जम गयी थी, उसे रूमाल से फोतेदार साफ करने में जुट गये। उस पर लिखा हुआ था—“हरियाणा में देवीलाल ने दिल्ली दरबार को नानी याद दिला दी।” अमिताभ ने सारे माहौल को अपनी लम्बी गर्दन घुमाकर एक बार देखा और उसके बाद जोर से ‘कट’ की आवाज लगाई। सारे दिल्ली दरबार की बत्तियां गुल हो गयीं। लेकिन पीछे खड़े दिल्ली दरबार के मूक समर्थक तालियां बजाते रहें। घुप्प अंधेरे में दिल्ली दरबार को ह्वील चेयर पर रखकर आधे दर्जन मेकअप मैनों के साथ अंदर ले जाया गया। घुप अंधेरे में पास खड़े दिग्विजय सिंह से अर्जुन सिंह ने फुसफुसा कर पूछा—“समधीजी, मेरी एक्टिंग कैसी रही! हिला दिया न सबको।” दिग्विजय ने अर्जुन सिंह के घुटनों को हाथ लगाते हुए कहा—“समधीजी, मैं तो आपका लोहा पहले से मानता हूं। इसीलिए अपनी बेटी आपके यहां ब्याही। वह एक वी०पी० सिंह का समधी आनन्द सिंह है। थाली का बैंगन। पहले उनके साथ था। अब घबरा कर दिल्ली दरबार की शरण में आ गया।” अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह के टकले सिर पर हाथ फेरते हुए कहा—“समधीजी, मक्खन न लगाओ। मुझे मालूम है, जब तुमको मौका मिलेगा, तो मेरे करीब से वैसे ही गायब होगे जैसे गधे के सिर से सींग। तुम-हम पहले पालिटीशियन हैं, बाद में समधी।” दिग्विजय सिंह हलका-सा मुस्करा कर अपने टकले सिर को खुजलाने लगे। दिल्ली दरबार के मूक समर्थक अब तालियों के साथ नारे लगाने लगे—“दिल्ली दरबार निर्भय हो, हम तुम्हारे साथ हैं।” अर्जुन सिंह को पसीना छूटने लगा—“यह क्या हो रहा है! मैं समझ रहा था कि ये मूक समर्थक मेरे प्रवचन से खुश होकर तालियां पीट रहे हैं। लेकिन ये लोग तो दिल्ली दरबार के साथ होने का नारा लगा रहे हैं। अब दिल्ली दरबार को पता चल जायेगा कि हम लोग नहीं, दिल्ली दरबार की मूल ताकत ये मूक समर्थक हैं। किसी तरह इनको चुप कराओ।” अर्जुन सिंह तुरन्त बूटा सिंह की तरफ बढ़े और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगे। पीछे से केसरजी ने पंजों के बल खड़े होकर दोनों के कंधों पर अपने हाथ टिका दिये। अंदर से फोतेदार और सतीश शर्मा निकल कर आये और फुसफुसाहट में शरीक हो गये। गोपी अरोड़ा, सरला ग्रेवाल को लेकर एक कोने में गमगीन होकर मंत्रणा में डूबने-उतराने लगे। मणिशंकर अय्यर नौकरशाही के हुजूम के साथ भागे-भागे आये और उन्होंने भी गोपी अरोड़ा वाला कोना पकड़ लिया। नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह के गोल से निकल कर एक कोने में औंधी पड़ी कुरसी को सीधा करके बैठ गये। उन्होंने अपनी चिंता का इजहार दांतों से नाखून काटने की प्रक्रिया शुरू करके करना शुरू कर दिया।

दिल्ली दरबार ने फोतेदार को एक झटका मारा, तो वह औंधे मुंह गिरे—“तू अपने को दिल्ली दरबार का लौह पुरुष समझता है। तुझे भी तेरी नानी याद दिलाये देता हूं। ले पकड़ यह इस्पात की जलती हुई लाल राड और यह पहिन खान में घुसने वाली लोहे की टोपी और फूट जा खान-इस्पात मंत्रालय में, अगर अब दिखायी पड़ा, तो तेरी ऐसी-तैसी कर दूंगा।”

सारे माहौल में भयंकर उदासी छा गयी। सभी की चिन्ता का मूल यही था कि अगर दिल्ली दरबार को पता चल गया कि उसकी मूल शक्ति यह मूक समर्थक ही हैं, तो वह हम लोगों की छुट्टी भी कर सकता है। जब-जब दिल्ली दरबार संकट में घिरा है, तो उसकी रक्षा इसी मूक समर्थन ने की है। अब लगता है कि फिर से दिल्ली दरबार की रक्षा के लिए मूक समर्थन उठ खड़ा हुआ है। तभी तो नारा लगा रहा है कि “दिल्ली दरबार निर्भय हो, हम तुम्हारे साथ हैं।”

संकट अब दिल्ली दरबार के ऊपर नहीं है, दरबारियों के ऊपर है—इस बात को गहराई से महसूस किया ही जा रहा था कि अचानक धू-धड़ाम की भयंकर आवाज के साथ पछाड़ खाते हुए अमिताभ बच्चन अंदर कमरे से बाहर आ गिरे। उनके पीछे दिल्ली दरबार ‘निर्भीकता का मेकअप’ किये हुए बिना बैसाखी के लपका—“...मैं तेरा खून पी जाऊंगा।” चल उठ, अभी अपना इस्तीफा इलाहाबाद लोकसभा सीट से लिख। तेरे भाई अजिताभ पर तो मैं जांच बैठा ही रहा हूं। माना मुझसे पूछ लिया था, तो क्या हुआ! अब मैं इनकार कर रहा हूं कि अजिताभ ने मुझसे पूछकर स्विट्जरलैंड में मकान नहीं खरीदा। तेरी तो ऐसी की तैसी। तू समझता है कि तू ही एंगरी यंग मैन का रोल कर सकता है। मैं तुझसे अच्छा करके दिखाऊंगा।” दिल्ली दरबार के बदले हुए तेवर देखकर पूरा वातावरण सहम गया। फोतेदार ने दिल्ली दरबार को पुचकारते हुए अपना कंधा सहारे के लिए आगे बढ़ाया। दिल्ली दरबार ने फोतेदार को एक झटका मारा, तो वह औंधे मुंह गिरे—“तू अपने को दिल्ली दरबार का लौह पुरुष समझता है। तुझे भी तेरी नानी याद दिलाये देता हूं। ले पकड़ यह इस्पात की जलती हुई लाल राड और यह पहिन खान में घुसने वाली लोहे की टोपी और फूट जा खान-इस्पात मंत्रालय में, अगर अब इधर दिखायी पड़ा, तो तेरी ऐसी-तैसी कर दूंगा।”

दिल्ली दरबार का ‘निर्भीकता का मेकअप’ देखकर सारे दरबारी तो तुरन्त फूट लिये। लेकिन रह गये मूक समर्थक नारा लगाते हुए—दिल्ली दरबार निर्भय हो, हम तुम्हारे साथ हैं।

—दरबारी लाल

सोनिया ने लिया बच्चन का इस्तीफा

सुपर स्टार अमिताभ बच्चन का अंत में लोकसभा से इस्तीफा मंजूर हो गया। लेकिन इससे पहले एक कोशिश यह हुई थी कि किसी तरह उनका इस्तीफा वापस हो जाये।

बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह पता चला कि दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक ने अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन के खिलाफ स्विटजरलैंड में भारतीय कानून 'फेरा' का उल्लंघन करके सम्पत्ति खरीदने का सबूत प्राप्त कर लिया है, तो प्रधानमंत्री सचिवालय में गहरी चिन्ता व्याप्त हो गयी। कहते हैं कि सोनिया गांधी ने यह सुझाया कि इस मामले को ठंडा करने के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दिला दिया जाये। वैसे उस समय प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार माखन लाल फोतेदार, सोनिया गांधी के इस सुझाव से बिलकुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इससे हमारी कमजोरी साबित होगी। उनका सुझाव था कि अगर अखबार में सबूत छपता है, तो करीब सौ इंका सांसदों का उसके खिलाफ बयान दिलाकर उसको आसानी से झुठलाया जा सकता है। लेकिन सोनिया का कहना था कि इससे काम नहीं चलेगा। अमिताभ का इस्तीफा जरूरी है।

कहते हैं कि उसके बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को फोन करके लोकसभा की सदस्यता से तुरन्त इस्तीफा भिजवा देने की सलाह दी। बताया जाता है कि रिलायंस के मालिक धीरू भाई अम्बानी के पुत्र मुकेश अमिताभ का इस्तीफा लेकर दिल्ली आये और उन्होंने उसे राजीव गांधी के हवाले किया। उस इस्तीफे को लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के पास भेज दिया गया। लेकिन इसके बावजूद फोतेदार तथा कुछ अन्य लोग राजीव गांधी को यह समझाने में लगे रहे कि अमिताभ का इस्तीफा स्वीकार न किया जाये। उससे कोई लाभ नहीं मिलनेवाला है। जब राजीव गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो फोतेदार ने अमिताभ के पिता डा० हरिवंश राय बच्चन तथा मां तेजी बच्चन से उनके, दिल्ली में गुल मोहर पार्क स्थित मकान पर जाकर मुलाकात की और कहा कि आप लोग खुद जाकर राजीव गांधी को समझायें कि अमिताभ का इस्तीफा स्वीकार न किया जाये। कहते हैं कि तेजी बच्चन तुरन्त मिलीं भी, लेकिन सोनिया ने उनकी एक बात नहीं मानी।

जब इंका कार्यसमिति की बैठक वी०पी० सिंह आदि के पार्टी से निकाले जाने का अनुमोदन करने के लिए बुलायी गयी, तो फिर राजीव गांधी को समझाया गया कि अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से इलाहाबाद की लोकसभा सीट खाली हो जायेगी और उस पर हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। इस समय राजीव गांधी का मन दुविधा में फंस गया। उन्होंने यह बात कार्य समिति की बैठक में रखी और अमिताभ बच्चन के इस्तीफे पर अंतिम फैसला अपने विवेक पर छुड़वा लिया। इधर तेजी बच्चन ने अमिताभ के पक्ष में इंका सांसदों के बीच हस्ताक्षर-अभियान चलवाने की पेशकश की। लेकिन इंका सांसदों ने हस्ताक्षर करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक राजीव गांधी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देते हैं, तब तक वे लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

उसके बाद २७ जुलाई को अमिताभ बच्चन बंगलौर में अपनी फिल्म की शूटिंग को छोड़कर दिल्ली आये। वह राजीव गांधी से मिले, तो उन्होंने कहा कि सोनिया से बात कर लो। सोनिया ने उनको सीधा लोकसभा अध्यक्ष के पास इस्तीफे की स्वीकृत देने के लिए भेज दिया। अमिताभ ने संसद भवन में सुबह ही ११ बजे के पहले बलराम जाखड़ से मुलाकात करके कहा कि "मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। जो इस्तीफा आपके पास आया है, उसे स्वीकार कर लें।"

अमिताभ बच्चन उसके बाद दो दिन तक अपने वंसत विहार स्थित मकान में रहे। लेकिन वह मात्र एक ही बार इस्तीफा देने के बाद राजीव गांधी से मिल पाये। लेकिन सोनिया से उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नही हो पायी।

हमारी गली अइयो ओ राजाजी

राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के उत्तर प्रदेश दौरे से भले ही राजा समर्थकों को कोई फायदा न हो, लेकिन जिस जिले में राजा जाते हैं, वहां की जनता के लिए वीर बहादुर सिंह और उनकी सरकार कुबेर का खजाना खोल देती है। यही वजह है कि अब जगह-जगह से राजा के पास ढेरों निमंत्रण आ रहे हैं, जिसमें उनसे आग्रह किया जा रहा है, 'हमारी गली अइयो ओ राजाजी।'

पिछले दिनों राजा हरिद्वार और मुजफ्फरनगर गये। वहां उन्होंने प्रदेश में व्याप्त सूखे की विकट समस्या से उदासीन वीर बहादुर सिंह और उनकी सरकार की जमकर खिचायी की। यही नहीं उन्होंने मुजफ्फरनगर के युवकों को सलाह दी, "जिस इलाके के ट्यूबवैल न चल रहे हों, वहां अफसरों का घेराव करें तथा सरकार को चलने न दें।" लेकिन इन युवकों को अफसरों के घेराव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले ही दिन वीर बहादुर सिंह का फरमान जारी हो गया, "मुजफ्फरनगर में अगर कोई भी ट्यूबवैल खराब मिला, तो संबंधित अफसर की नौकरी गयी।"

तीन दिनों के अन्दर ही मुजफ्फरनगर के न केवल सभी ट्यूबवैल चल गये वरन वहां अब चौबीसों घंटे बिजली मिलने लगी है। इसी के बाद वीर बहादुर सब काम छोड़ सूखे की समस्या के समाधान में जुट गये। विभागीय सचिवों और मंत्रियों को गांव-गांव जाकर सूखा पीड़ितों की सहायता का निर्देश दे दिया गया। यही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत राजा के साथ न जाने पायें, वीर बहादुर ने न केवल इसकी पूरी पेशबंदी की वरन टिकैत को पटाकर अपने साथ कर लिया है।

अपने राष्ट्रपति जीवन के आखिरी दिनों में अपने बयान से हर दिन देश में एक नये उतार-चढ़ाव को जन्म देने वाले ज्ञानी जैल सिंह २५ जुलाई को राष्ट्रपति भवन से ससम्मान विदा होकर सर्कुलर रोड गये और उनकी इस विदाई के साथ ही देश के नये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामास्वामी वेंकटरमण राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर राष्ट्रपति भवन में आ गये। वैसे तो वह कांग्रेस की उम्मीदवारी से राष्ट्रपति चुने गये हैं, पर वेंकटरमण एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनसे देशवासी आशा लगाये बैठे हैं कि वह राष्ट्रपति की कुरसी पर बैठकर किसी सत्ता या पार्टी के हित में नहीं, बल्कि देश हित में सही निर्णय लेंगे। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा भी है कि उनके लिए देश का संविधान और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि है। राष्ट्रपति चुने जाने पर उनके अभिनंदन के दृश्य।

विश्वनाथ प्रताप सिंह अब एक नाम नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनांदोलन का वह पर्याय बन गये हैं। पार्टी से निष्कासन के पहले उनकी जबान पर वफादारी का ताला पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन निष्कासन के बाद उन्होंने राजीव गांधी पर सीधा वार करना शुरू कर दिया है। १२ अप्रैल को वित्त मंत्रालय से इस्तीफा देने के बाद जब वह पहली दफा १२ मई को इलाहाबाद आये थे और पी०डी० टंडन पार्क में जनसभाओं के सिलसिले का श्रीगणेश किया था, तो नारा लगा था—'राजा-राजीव जिंदाबाद'। लेकिन २६ जुलाई को मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक जनसभा में नारे लग रहे थे–'राजीव गांधी देख लो जनता किसके साथ है; तख्त बदल दो ताज बदल दो', बेईमानों का राज बदल दो। मुजफ्फरनगर

छाया : मनमोहन शर्मा

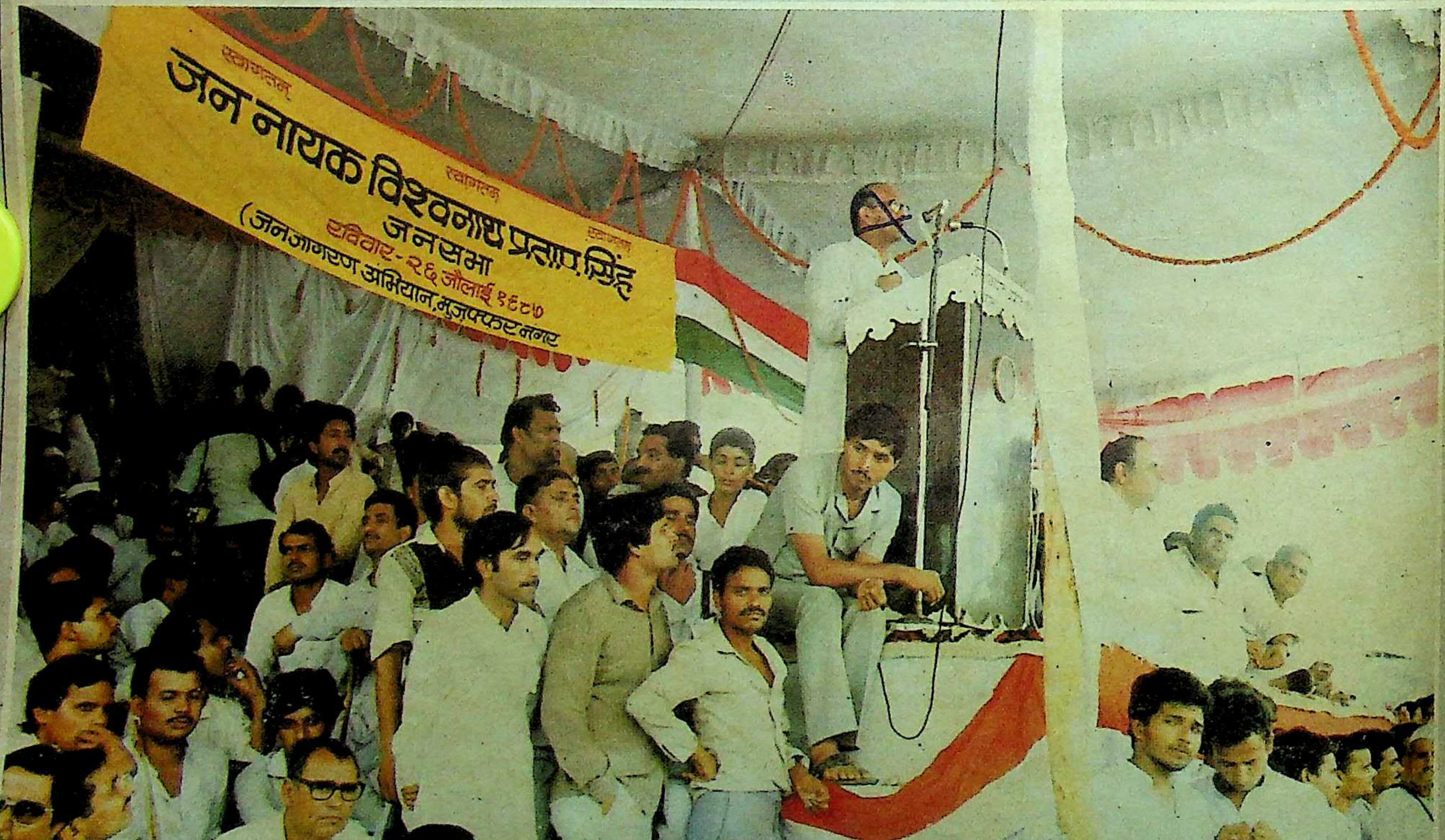
जन नायक विश्वनाथ प्रताप सिंह
जनसभा
रविवार - २६ जौलाई १९८७
(जनजागरण अभियान, मुज़फ्फर नगर

की जनसभा में उनके साथ मंच पर भागीदारी कर रहे थे—अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, सतपाल मलिक, रामधन आदि।

मुजफ्फरनगर की इस जनसभा के बाद यह चर्चा आम हो गयी है कि क्या वी०पी० सिह का 'जनजागरण अभियान' १९७४ के जे०पी० आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है? क्योंकि वी०पी० सिह की जनसभाओं में भीड़ सरकारी साधनों के जरिये घेर कर नहीं लायी जाती, बल्कि हजार दिक्कतें सहकर स्वेच्छा से उनकी सभाओं में उमड़ती है। इन लोगों में युवकों की संख्या ज्यादा होती है जो कि जे०पी० आंदोलन के मुख्य आधार थे। मुजफ्फरनगर के लिए राजा दिल्ली से रवाना हुए थे और उनके पीछे कारों का अटूट काफिला था। रास्ते भर उनके प्रति जनता के अपार स्नेह और विश्वास का दृश्य देखते ही बनता था।

छाया : इमेज क्रिएटर

गीत सेठी बिलियर्ड्स की दुनिया का वह नाम है, जिसने इतिहास बनाया है—रिकार्डों की कतारें खड़ी की हैं। एक जमाने में हाकी और क्रिकेट की उपलब्धियों से ही भारत और भारतवासी गर्व का अहसास करते थे, पर आज एथलेटिक्स, शतरंज और बिलियर्ड्स तक उपलब्धियों का सरताज भारत के सिर पर है। ७ अगस्त, १९८५ को गीत सेठी गैरनामांकित खिलाड़ी के रूप में जब पहली बार बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप में भाग लेते हुए मार्शल और माइकल को पराजित करके विश्वविजेता बने थे, तो चौंकानेवाला सुख था, पर इस बार २ अगस्त को उत्तरी आयर लैंड में बेलफास्ट के पार्क व्यू होटल में आयोजित चैंपियनशिप में तीसरी सीडिंग प्राप्त माल्टा के जो ग्रेच को १६०० से अधिक अंकों से पराजित करके वह एक बार फिर बिलियर्ड्स विश्वविजेता बने, तो पूर्व में चौंकानेवाला सुख द्विगुणित हो गया। जहां गीत सेठी को दूसरी बार विश्वविजेता बनने का गौरव मिला है, वहीं भारत के लिए भी सम्मान की बात रही कि लगातार पांचवीं बार वह विलियर्ड्स विश्वविजेता का खिताब हासिल कर सका। विश्वविजेता का दूसरी बार खिताब जीतकर गीत सेठी ने जहां एक ओर पूर्व विश्वचैंपियन विल्सन जोंस की बराबरी कर ली है, वहीं माइकल फरेरा के लगातार तीन बार विश्व खिताब जीतने की बराबरी करने से वह अब केवल एक खिताब पीछे हैं। सेठी को विश्वास है कि वह इस रिकार्ड को भी तोड़ेंगे और नये रिकार्ड बनायेंगे।

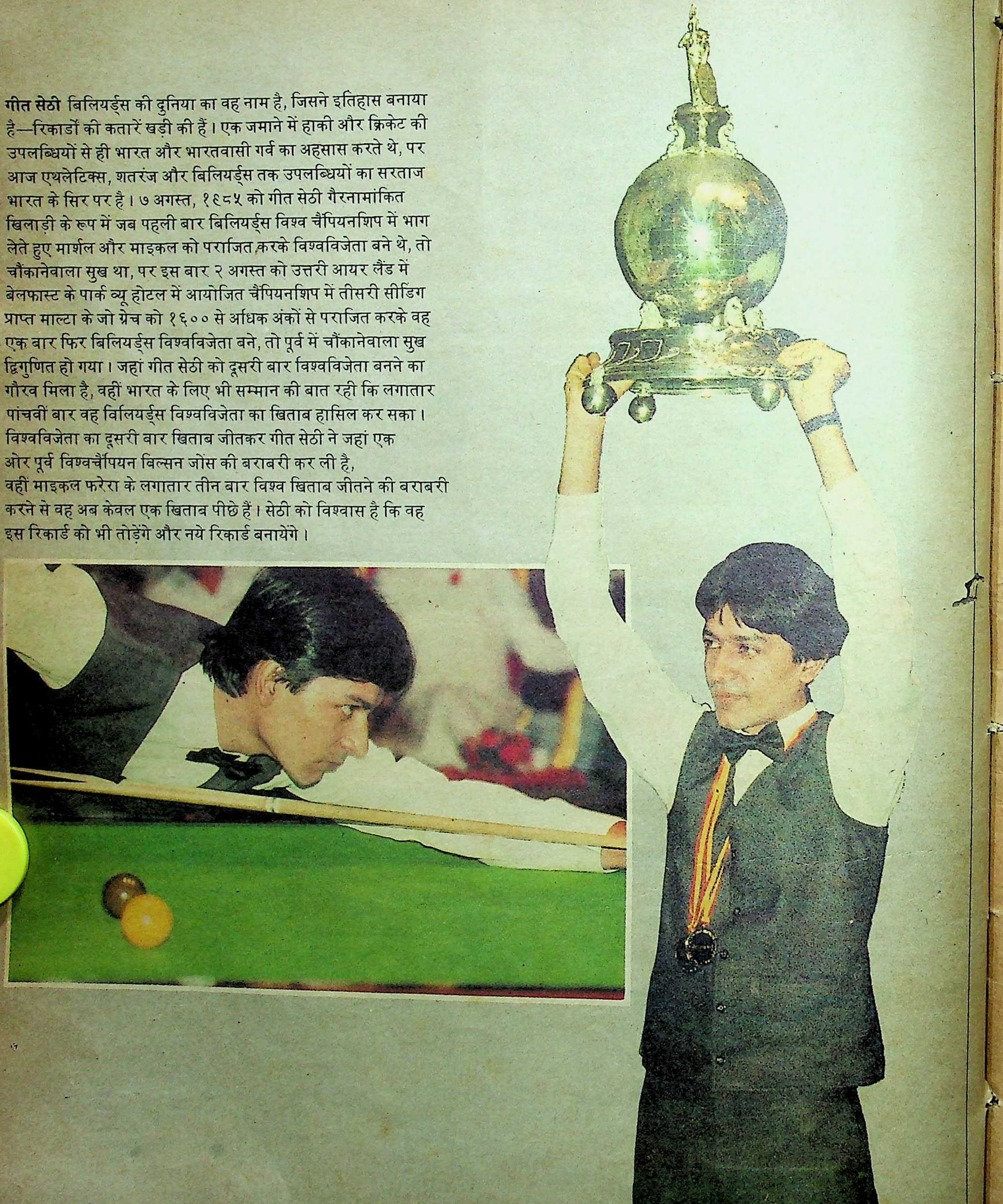

बंदर बनेंगे घरेलू नौकर

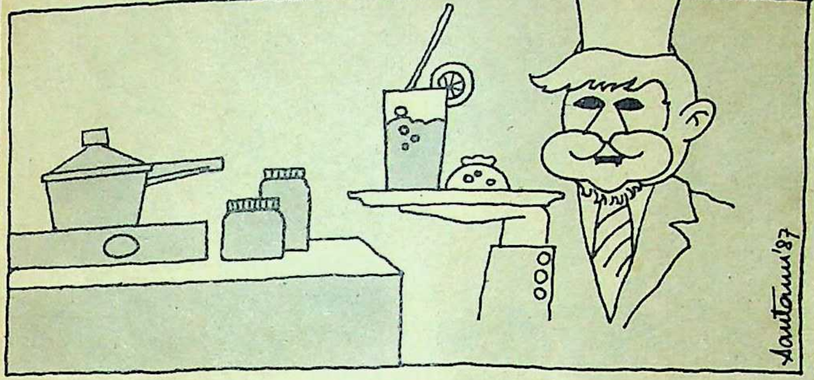

बंदर को जानवरों में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और पश्चिमी देशों में तो काफी सारे लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं। इसी आधार पर कहनेवाले तो यहां तक कहते हैं कि बंदर मनुष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने 'सुपर बंदर' अर्थात् मनुष्य का सृजन किया, लेकिन युग बीतते चले गये, मनुष्य किसी 'सुपर मनुष्य' को पैदा नहीं कर सका। बहरहाल, महर्षि अरविंद जैसे दार्शनिकों ने 'सुपर मनुष्य' के पैदा होने की भविष्यवाणियां कर रखी हैं। भारत में बंदर 'हनुमान सेना' के रूप में जाने-जाते हैं, लेकिन इतनी ख्याति के बावजूद बंदर की बुद्धिमत्ता का कोई उपयोग मनुष्य के हित में नहीं हो पाया था, सिवाय इसके कि उसके शरीर में विभिन्न रोगों का संक्रमण करके प्रयोग किये जाते थे। लाखों बंदर अकेले अमरीका में ही इन प्रयोगों के तहत मार डाले जाते थे—लेकिन अमरीका के कोलंबिया प्रांत के एक संस्थान 'हेल्पिंग हैंड्स' (सहयोगी हाथ) ने बंदरों की बुद्धिमत्ता के सार्थक उपयोग का कार्य भी शुरू कर दिया है।

यह संस्था कपूशी जाति के बंदरों को छह मास का प्रशिक्षण देकर घरेलू कामकाज के लिए उपयोगी बना देती है। कैसे बंदर अभी ऐसे विकलांगों को घरेलू जरूरतों में सहायक होने के लिए दिये जाते हैं, जो घर में अकेले रहते हैं और अपने हाथ से कामकाज नहीं कर सकते। ये बंदर खाने का सामान मेज पर रखने, मेज से खाली प्लेटें हटाने, दरवाजा व बिजली का स्विच खोलने और बंद करने का काम बखूबी करते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं आता, वे सफाईपसंद होते हैं, प्यार प्रदर्शित करने के लिए हाथों को चूमते हैं। अभी इन बंदरों को विकलांगों का सहयोगी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि इन्हें एक अच्छा घरेलू नौकर बनाया जा सकता है। बहुत संभव है कि २१वीं संदी में घरों में घरेलू नौकरों की जगह ये बंदर ले लेंगे और बंदरों को प्रशिक्षित करने का काम एक उद्योग के रूप में चलने लगेगा। 'बंदर नौकर', 'मनुष्य नौकरों' से इसलिए भी बेहतर साबित होंगे, क्योंकि इनके साथ वेतन की झिकझिक और चोरी का डर नहीं रहेगा।

ताकि तलाक न लें

'उन्मुक्त सेक्स' के मामले में बहुत खुले विचार रखने के लिए विख्यात स्वीडन सरकार ने दो दशक पहले जनसंख्या-नियंत्रण के लिए अनेक रोचक कदम उठाये थे। स्वीडिशवासियों को कम-से-कम छुट्टियां लेने की सलाह दी जाती थी, जिससे वे पिकनिक आदि 'रोमांटिक माहौल' पैदा करनेवाले आयोजनों से जहां तक हो सके दूर रह सकें—स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सेक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी थी। लेकिन इससे स्वीडन का घरेलू ढांचा ही चरमरा उठा। जनसंख्या में नये बच्चों की कमी से भारी असंतुलन पैदा हो गया। वहां होनेवाले हर सात विवाहों में से चार विवाह टूट जाते हैं। तलाक ही नहीं वहां नाजायज बच्चों की बाढ़ सी आ गयी थी। १९८४ में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार उस वर्ष स्वीडन में पैदा होनेवाले कुल बच्चों में ४६ प्रतिशत नाजायज बच्चे थे। स्वीडन सरकार ने अब 'उन्मुक्त सेक्स' से तौबा कर ली है और उसने मर्यादित पारिवारिक जीवन को प्रोत्साहित करने और जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की है।

अब कामकाजी स्वीडिश-दंपति १२ मास का प्रसव अवकाश ले सकते हैं, इस दौरान पहले नौ मास तक उन्हें वेतन का ९० प्रतिशत और शेष अवधि के लिए २४० डालर दिये जायेंगे। १६ वर्ष से कम आयु की पहली संतान की परवरिश के लिए सरकार ९६० डालर प्रतिवर्ष भत्ता देगी, दूसरी संतान पर इससे ५० प्रतिशत अधिक, तीसरी संतान पर १०० प्रतिशत अधिक इसी प्रकार चौथी-पांचवीं...संतानों पर सरकारी भत्ता बढ़ता जायेगा। स्वीडिश सरकार को उम्मीद है कि इन सुविधाओं से वहां तलाक काफी हद तक रुक जायेंगे और नाजायज बच्चों व जनसंख्या की कमी से यह देश निजात पा जायेगा।

कुत्तों की राजनीति

राजनीति में नेकनामी और बदनामी दोनों एक ही प्रकार का फल देते हैं, वह यह कि इससे नाम रोशन हो जाता है और जिनका नाम रोशन हो जाता है, वह राजनीति के काबिल माना जाता है, भले ही वह नाचने-गाने व ठुमका लगाने के लिए रोशन हो या तस्करी के लिए। राजनीति में कुत्ते 'शांत वफादार के आदर्श' के रूप में स्थापित थे, लेकिन जाने क्यों प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इन्हें 'बिलावजह भौंकने' के लिए बदनाम करके राजनीति करने के लिए छोड़ दिया है।

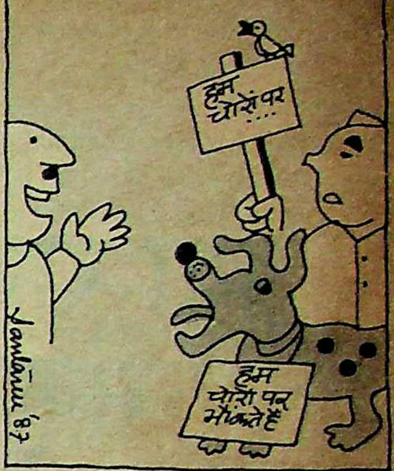
हम चोरों पर ....
हम चोरों पर भौंकते हैं

इंदौर के कुत्तों को प्रधानमंत्री के इस कथन पर कि 'मैं हर भौंकनेवाले कुत्ते का जवाब नहीं देता' कुछ खास ही गुस्सा आ गया। गोया वे बिलावजह भौंकते हैं, जबकि असलियत यह है कि वे चोरों को देखकर भौंकते हैं। —बस फिर क्या था उन्होंने गलों में 'हम चोरों पर भौंकते हैं' की दफ्तियां लटकाकर विरोध प्रदर्शन करने का निश्चय किया। स्थानीय जनता पार्टी और युवा जनता के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुत्तों के इस जुलूस का नेतृत्व संभाला। स्थानीय शासन ने कुत्तों के डर से इस विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन विरोध-प्रदर्शन हुआ। १२ कुत्तों के साथ जनता पार्टी के २२ कार्यकर्ताओं ने भी गिरफ्तारी दी। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसीं।

जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इन कुत्तों को जेल में राजनीतिक दर्जा दिलाने के लिए भी आंदोलन किया। कुछ कार्यकर्ताओं को संदेह है कि पुलिस हिरासत में इन कुत्तों को जान से मार डाला गया है—जब अच्छे-भले आदमी का वहां बच पाना संभव नहीं है, तो सरकार के लिए आदमी से अधिक खतरनाक हो गये इन कुत्तों को सुरक्षित छोड़ देना कैसे मुमकिन है। उन्हें यह भी शिकायत है कि कांग्रेस पार्टी में हर रोज आपसी कलह के कारण भौं-भौं की आवाज सुनाई देती है, तो उनकी सरकार को कुत्तों के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का क्या अधिकार है?

—संयोजन : विनोद मिश्र

क्या राजीव गांधी संकट से उबर पायेंगे ?

राजीव गांधी ने नयी शैली और भारी धमाके के साथ राजनीति में प्रवेश किया था। धोती-कुरता और टोपीधारी राजनीतिक जागीरदारों की जगह उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के अत्याधुनिक विचारों व सफारी सूटधारी अपने दोस्तों को स्थापित किया था। चरखे के स्थान पर उन्होंने कंप्यूटर संस्कृति का सूत्रपात किया था। प्रचंड बहुमत और स्वच्छ छवि उनकी सबसे बड़ी थाती और जनता का अपूर्व विश्वास उनकी प्रेरणा का अजस्र स्रोत था। लेकिन ढाई साल के भीतर-भीतर यह सब धराशायी होता नजर आ रहा है। यद्यपि संसद में प्रचंड बहुमत आज भी उनके पास है, फिर भी सत्ता उनके हाथ से खिसकती नजर आ रही है। इस भारी झटके के बाद यद्यपि उन्होंने अब अपनी रणनीति और कार्यशैली में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो क्षति हो चुकी है, क्या उसकी वह पूर्ति कर पायेंगे ? :

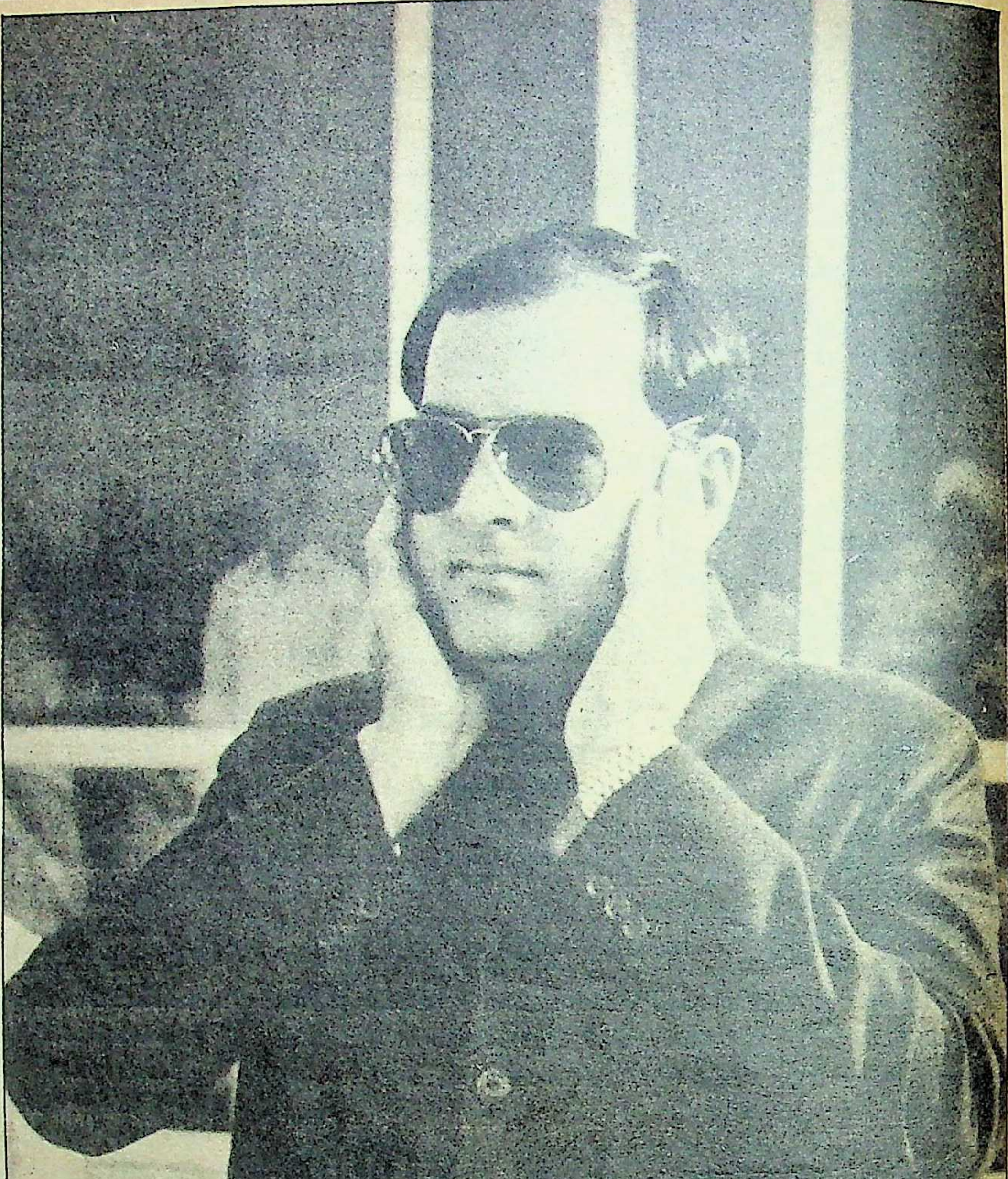

मित्रमंडली से तौबा : राजीव गांधी

देश के एक धमाकेदार साप्ताहिक के नामी-गिरामी संपादक अपनी पिछली दिल्ली यात्रा में गिने-चुने मित्रों से रहस्योद्घाटन कर रहे थे कि—बोफोर्स ने लंदन के कुछ पत्रकारों को वे नाम बता दिये हैं, जिन्हें ३५ से ५० करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया था। संपादक के अनुसार नाम तीन हैं। दो नाम इतालवी हैं और भारत के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से संबंधित हैं। तीसरा नाम भारतीय मूल का है, उसका धारक, प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूरोप में बसा हुआ है और अजिताभ बच्चन से पारिवारिक रिश्ते से जुड़ा है। इन मित्रों-सूत्रों का कहना था कि इन नामों और उनके पीछे की रहस्यमयी कथाओं का भारत में उद्घाटन कुछ ही सप्ताहों की बात है।

एक केन्द्रीय मंत्री से इसकी चर्चा हुई, तो वह चौंके। उनकी प्रतिक्रिया थी कि यदि यह सच है, तो 'यह राजनीतिक डाइनामाइट होगा'। वह इससे भी सहमत थे कि यदि यह सिद्ध हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत राजीव गांधी को बचा नहीं पायेगी।

यह भी उन दर्जनों अफवाहों में से एक हो सकती है जो पिछले मार्च से लगभग हर समय राजधानी के राजनीतिक क्षेत्रों में बारी-बारी से गर्म और ठंडी होती रहती हैं। ऐसी ही एक अफवाह इस संवाददाता को पैरिस में बैठे एक मित्र ने फोन पर सुनायी। फ्रांसीसी पत्रकारों में यह चर्चा प्रचलित थी कि राजीव गांधी ने भारत से भागने की व्यवस्था कर ली है। किंतु यह शंका केवल विदेशों तक ही सीमित नहीं थी। 'माया' से एक खुली बातचीत में एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद बड़ी गंभीरता से पूछ रहे थे, "लेकिन यदि स्थितियां ज्यादा बिगड़ीं, तो राजीव गांधी भारत में रुकेंगे भी कि नहीं, या बाहर चले जायेंगे?" यह सांसद कोई कल्पनाथ राय-कोटि के नहीं थे। केन्द्र में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, सितंबर में प्रतीक्षित परिवर्तन में मंत्रिपद के सशक्त प्रत्याशी हैं और एक गंभीर, मननशील राजनीतिज्ञ, के रूप में जाने जाते हैं।

ये दोनों चर्चाएं उस समय की हैं, जब देश के नित्य-परिवर्तनशील राजनीतिक क्षितिज पर बहुत कुछ घट रहा था। राजीव गांधी २९ जुलाई को कोलम्बो में राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ ऐतिहासिक भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। अगले दिन विदाई 'गार्ड आफ आनर' में एक सिंहली नौ-सैनिक द्वारा उन पर हमले की अप्रत्याशित घटना को करोड़ों भारतीय दूरदर्शन पर देख चुके थे और उससे उपजी सहानुभूति समझौते पर देशव्यापी प्रशंसा के साथ मिलकर उनकी राजनीतिक पूंजी बन चुकी थी, सरकार के अस्तित्व का संकट टल चुका था, ज्ञानी जैल सिंह ऐन वक्त पर कोई अप्रिय हरकत न करके राष्ट्रपति भवन वेंकटरमण के लिए खाली कर गये थे और वी०पी० सिंह के दक्षिण भारत, गुजरात और उत्तर भारत के दौरों के बावजूद उनको और अरुण नेहरू, आरिफ, विद्याचरण शुक्ल के निष्कासन को लेकर जुलाई में तूफान थमा तो नहीं था, किंतु सम पर अवश्य आता जा रहा था।

प्रत्याक्रमण : मार्च से जुलाई तक एक के बाद एक आरोपों, हमलों और संकटों से जूझते राजीव गांधी ने अगस्त में सुरक्षात्मक रवैया छोड़ अचानक आक्रामक तेवर अपना लिया था। कई महीनों से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपने दल, नेता और अपने आपको जनता की अदालत के कटघरे में खड़े अपराधी सा हताश महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि राजीव गांधी कभी तो आरोपों का समुचित उत्तर देंगे। युवा प्रधानमंत्री ने जब अंततः प्रत्याक्रमण का फैसला किया, तो शेर को सीधे उसकी मांद में चुनौती देकर।

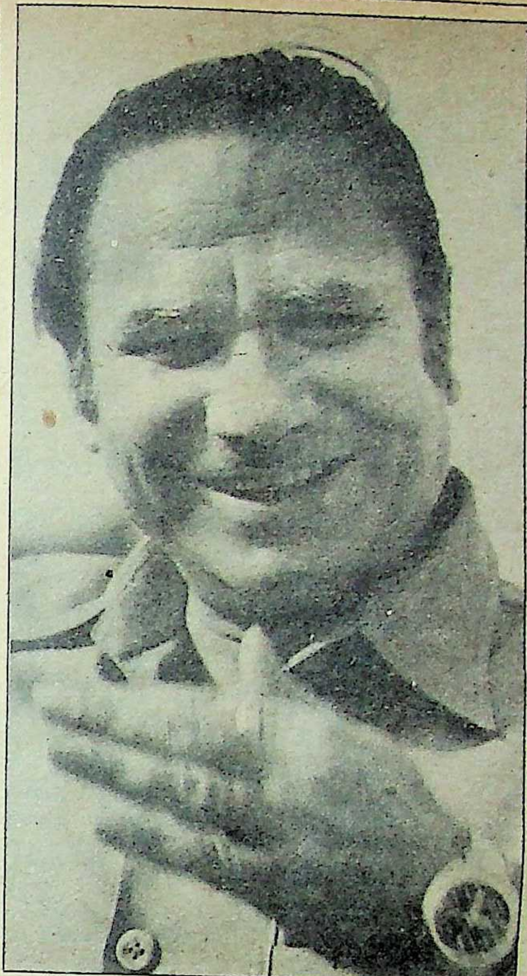

पदावनत : फोतेदार

छाया : क्रिएटिव आई

> अरुण
>
> नेहरू के हटने के बाद से फोतेदार की शक्ति कई गुना बढ़ गयी थी। तकनीकी रूप से उनका काम तो वही रहा जो पहले था, लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री के विश्वस्त व अंतरंग लोगों में अकेले वही रह गये थे, इसलिए वह धीरे-धीरे लगभग उस जगह पर आते जा रहे थे, जिस पर इंदिरा गांधी के जमाने में आर०के० धवन हुआ करते थे।

एक अगस्त की इलाहाबाद की सभा में जब राजीव गांधी बोल रहे थे, तो लगभग दो लाख श्रोता थे, भले ही उसमें एक बड़ी संख्या स्कूली बच्चों की थी। उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों की मेहनत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रयासों और मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की व्यवस्था के चलते भले ही प्रदेश-भर के लोगों को उस दिन बसों के दर्शन न हुए हों, लेकिन कानपुर, लखनऊ और आजमगढ़ जैसे दूरस्थ स्थानों से आये लोगों ने राजीव गांधी को अपने प्रत्याक्रमण का आरंभ एक 'विशालकाय' सभा से करने का संतोष अवश्य दे दिया।

विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के लिए बड़े खतरे और प्रतिद्वंद्वी हैं और इलाहाबाद उनका घर है। इलाहाबाद कांग्रेस में राजा मांडा के प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थक और उनसे अघोषित सहानुभूति रखने वाले, दोनों ही काफी हैं। इसलिए वहां इतनी बड़ी सभा करके उन्हें पार्टी और देश-विरोधी (जयचंद-मीरजाफर) कहने में एक स्पष्ट सांकेतिकता थी, एक निहित संदेश था।

किंतु राजनीति की धाराएं एकाध जनसभाओं से तो बदला नहीं करतीं। बदलती हैं राजनेता या पार्टी की जनता में छवि से। राजीव गांधी के आक्रामक भाषण से इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के निवासियों में उनकी छवि कितनी निखरी और वी०पी० सिंह की कितनी बिगड़ी, यह तो भविष्य बतायेगा, किंतु जिस एक व्यक्ति को उस सभा से सीधा लाभ हुआ, वह थे मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह। उनकी डगमगाती नैया को इतनी 'सफल' सभा करवाने के पुरस्कार स्वरूप कुछ समय और मिल गया।

विश्वनाथ प्रताप सिंह पर जवाबी हमला करने में राजीव गांधी थोड़ा पिछड़ गये हैं। जिस समय वह नैनी (इलाहाबाद) में गरज रहे थे, उस समय उनकी गर्जना का मुख्य निशाना सुदूर दक्षिण, बंगलौर, में बैठा देश में मध्यावधि चुनावों की मांग कर रहा था। कल्पनाथ राय और के०के० तिवारी जैसे अपने हास्यास्पद रक्षकों की व्यर्थता को पहचान कर जब तक प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों ने यह तय किया कि वी०पी० सिंह की चुनौती का मुकाबला उन्हें स्वयं आगे आकर करना होगा, तब तक विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने पटना, अरवल, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के दौरों से लगभग आधे उत्तर भारत में अपनी बढ़ती लोकप्रियता की विजय पताका फहरा कर अछूते दक्षिण की ओर प्रस्थान कर चुके थे।

बोफोर्स की पहेली राजीव गांधी के लिए यक्ष-प्रश्न बन चुकी है, यानी जीवन-मरण का प्रश्न। १७०० करोड़ रुपए के इस विराट अस्त्र सौदे और उसमें उन पर तथा उनके निकट संबंधियों-मित्रों की

भूमिका पर जो प्रश्न आज भारत के ग्रामवासियों तक पहुंच गये हैं, उनका उचित समाधान ही राजीव गांधी को राजनीतिक अवसान से बचा सकता है। पर इस प्रश्न पर राजीव सरकार एक खुला रुख अपनाने से जिस तरह कतरा रही है, उससे आशंकाएं पुष्ट ही होती हैं। बोफोर्स का प्रश्न इस समय भारतीय राजनीति में किस सीमा तक महत्वपूर्ण हो गया है, यह संसद के मानसून सत्र ने सिद्ध कर दिया।

इस सावन में दो महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित हुए। पूरी जुलाई और अगस्त भर गायब रहकर वर्षा ने पिछले ८० वर्ष का रिकार्ड तोड़ा। पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं ने जिस झुलसाने वाली सूखी गर्मी से राजधानीवासियों को तपाया, उसी तीव्रता की गर्मी संसद के वातानुकूलित सदनों और कक्षों में थी। २७ से ३१ जुलाई का पहला सप्ताह भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व था।

यह तो पहले से तय था कि यह सत्र भरपूर हंगामी होगा। लेकिन हंगामा ऐसा और इतना लंबा होगा, यह कल्पना किसी को नहीं थी। पहले दिन तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को श्रद्धांजलि देकर सदन स्थगित हो गया, किंतु दूसरे दिन २८ से ३१ जुलाई तक जो अराजकता चली, वह अपनी उग्रता में अपूर्व थी।

संसद में पहली बार लगातार चार दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, पहली बार वक्तव्य पढ़ते हुए एक मंत्री के हाथ से कागज छीन लिये गये और शायद दूसरी बार एक सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित (बाद में वापस) किया गया (इससे पहले इंदिरा गांधी को १९७८ में किया गया था)।

इस सारे हंगामे की जड़ में था बोफोर्स। यह जानते हुए भी कि स्वस्थ संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है, संसद की मर्यादा धूमिल हो रही है, विपक्ष संसद की कार्यवाही न चलने देने के लिए कटिबद्ध था, तो इसलिए कि उसे पता था कि यदि यह अवसर हाथ से निकल गया, तो बोफोर्स कांड की सच्चाई उजागर करने का अंतिम अवसर उसके हाथ से निकल जायेगा। मुद्दा था सरकार द्वारा बोफोर्स सौदे और उसमें कमीशन के मामले में जांच करने के लिए घोषित संसदीय समिति का गठन।

सरकार ने समिति के गठन के लिए जो सिद्धांत प्रस्तावित किया था, वह संसद में कांग्रेस तथा विपक्ष की शक्ति के आधार पर आनुपातिक चुनाव का था। उसके अनुसार लोकसभा की १४ सदस्यीय समिति में विपक्ष से अधिक से अधिक २ सदस्य होते और शेष १२ कांग्रेस के। इन दो में से भी यदि एक अन्नाद्रमुक का हो जाता (जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है), तो विपक्ष का कुल एक ही सदस्य रहता। जाहिर है बोफोर्स जांच और उसके संभावित परिणामों के महत्व को देखते हुए विपक्ष जांच समिति में अपनी नाममात्र की उपस्थिति स्वीकार नहीं कर सकता था।

इसलिए विपक्ष की जिद थी कि जांच समिति की संदर्भ शर्तों को और व्यापक बनाया जाये, समिति में विपक्ष के अधिक सदस्य लिये जायें और उसका अध्यक्ष भी किसी विपक्षी नेता को बनाया जाये। यदि यह नहीं होगा, तो संपूर्ण विपक्ष समिति का और पूरे सत्र का बहिष्कार करेगा।

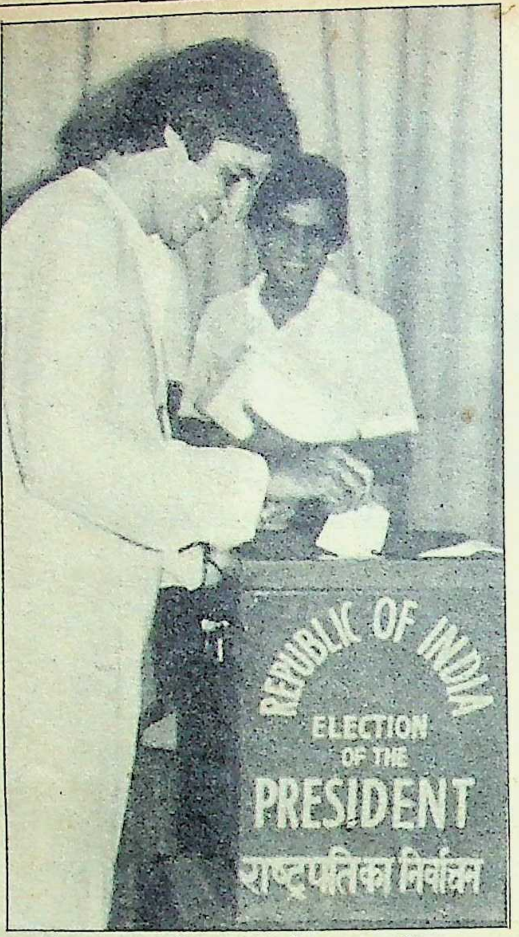

छुट्टी, मगर काफी नुकसान के बाद : अमिताभ

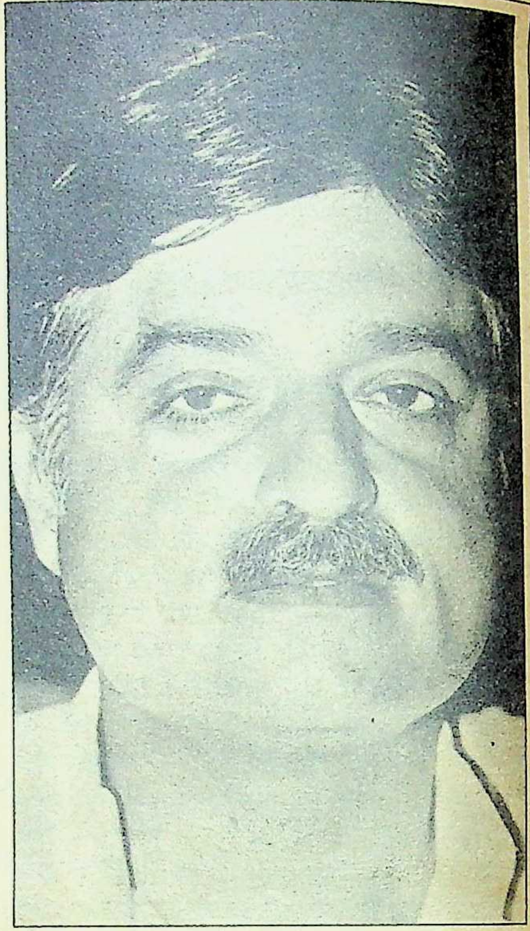

कब तक ? : सतीश शर्मा

अमिताभ बच्चन के राजनीतिक उदय और अवसान की कहानी सबसे ताजी है, इसलिए उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अरुण नेहरू और अरुण सिंह के विपरीत संसद से त्यागपत्र देने के बावजूद अमिताभ बच्चन राजीव के आज भी काफी करीब हैं।

कैप्टन सतीश शर्मा अब भी प्रधानमंत्री निवास में बैठते हैं, लेकिन यह सर्वविदित है कि शिखर राजनीति में उनका हस्तक्षेप और भूमिका नगण्य है। वह राज्यसभा सदस्य अवश्य हैं, किंतु शिखर राजनीति के हाशिये पर आ गये हैं।

इस प्रश्न पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में काफी विचार-विमर्श चला। यह तो कांग्रेस भी जानती थी कि विपक्षी दलों को कुछ तो देना पड़ेगा, अन्यथा वह सदन चलने नहीं देंगे। किंतु उसके लिए भी आरंभ में अस्वीकार की मुद्रा आवश्यक थी, ताकि विपक्ष आरंभिक विजय से उत्साहित होकर अपनी मांगें न बढ़ा दे। इसलिए सप्ताहांत के साथ ही विपक्ष से वार्ताएं आरंभ हो गयीं और दूसरे सप्ताह तक सरकारी पक्ष विपक्ष की मांगों को एक सीमा तक मानने के लिए अंदर से तैयार हो गया था।

फोतेदार की अवनति : माखन लाल फोतेदार का केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री बनना और भारत-श्रीलंका समझौता—ये दो घटनाएं अरुण सिंह के इस्तीफे के बाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। फोतेदार का प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के पद पर से हटकर मंत्री बनने के पीछे छिपे निहितार्थ के बारे में आज भी कांग्रेसियों में चर्चाएं हो रही हैं। बहुत से लोग यह नहीं मान पा रहे कि आर०के० धवन के हटाये जाने के बाद से उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनते गये फोतेदार को इस तरह सहसा शक्ति हीन बनाकर कैबिनेट मंत्री-पद की लालीपॉप थमायी जा सकती है।

प्रधानमंत्री निवास के अकसर चक्कर लगाने वाले एक सांसद का कहना था कि मंत्री बनने के बाद भी फोतेदार उन्हें प्रधानमंत्री कक्ष के आसपास मंडराते हुए दिखे थे। किंतु अनुभवी और जानकार लोगों में इस घटना का सही मतलब और महत्व स्पष्ट था। साथ ही थी एक खुली प्रसन्नता। एक केन्द्रीय मंत्री ने 'माया' से टिप्पणी की, "यह निस्संदेह फोतेदार की

राजनीतिक पदावनति है। हालांकि उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं, राज्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। अब इस्पात और खान मंत्रालय जैसे विभाग में उनकी प्रशासनिक अक्षमता भी उजागर हो जायेगी।" इस घटना से खुश एक अन्य वरिष्ठ सांसद की भविष्यवाणी थी कि अगले चुनावों से कुछ समय पहले होने वाले मंत्रिमंडलीय फेरबदल में फोतेदार पूरी तरह से हटा दिये जायेंगे।

जुलाई के अंतिम शनिवार को जब कई कांग्रेसी सांसदों को फोन पर शाम ६.४० पर राष्ट्रपति भवन पहुंचने के संदेश मिले, तो कई सप्ताह से चली आ रही आशाओं को पर मिल गये। बहुत से सांसद शपथ ग्रहण के लिए तैयार रखी अचकनें और बंद गले के सूट पहन कर पहुंचे थे। सबको आशा थी कि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडलीय विस्तार और फेरबदल शायद उसी शाम होने वाला था। किंतु ६.४० पर आरंभ हुई कार्यवाही संक्षिप्त थी और ७ बजे राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने वाले सभी कांग्रेसियों के चेहरों पर निराशा थी। ऊर्जा मंत्री वसन्त साठे डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी के साथ बाहर खड़े अपनी कार का इंतजार कर रहे थे। 'माया' ने उनसे पूछा, "यह तो फोतेदार की राजनीतिक पदावनति लगती है।" साठे की टिप्पणी थी, "गुड थिंग (अच्छी बात है)।"

उस सारी शाम राजनीतिक क्षेत्रों में यही चर्चा थी कि पिछले कई महीनों में धीरे-धीरे लगभग सर्वशक्तिमान बन गये फोतेदार को अचानक मंत्री क्यों बना दिया गया। कारण खोजना बहुत कठिन नहीं था। जैसा कि 'माया' ने पिछले अंक में संकेत दिया था, पिछले कई महीनों से धीरे-धीरे कांग्रेस में फोतेदार के विरुद्ध असंतोष और रोष बढ़ता जा रहा था और प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर उ लोगों ने भी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उन . फोतेदार की शिकायतें खुलकर करना आरंभ कर दिया था जो पहले राजीव गांधी के सामने मुंह खोलने का भी साहस नहीं कर पाते थे।

चुनौती : मुजफ्फरनगर में वी०पी० सिंह,

छाया : इमेजक्रिएटर

शिकायतें अनुचित नहीं थीं। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के रूप में फोतेदार का वास्तविक काम उनके और शेष पार्टी के बीच पुल का काम करना था। वह प्रधानमंत्री की आंख और कान थे, दिमाग नहीं। उनसे अपेक्षित केवल यह था कि पार्टी के नेताओं, गुटों की भावनाओं, सूचनाओं शिकायतों और सुझावों को प्रधानमंत्री तक अविकल रूप में पहुंचायें। लेकिन जिस ढांचे में प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच ही अपने आप में जबरदस्त शक्ति का स्रोत होती है, वहां फोतेदार दिन-रात प्रधानमंत्री के साथ समान्तर केन्द्र बन गये थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, मंत्रिमंडल में, कांग्रेसी राज्य सरकारों में और प्रदेश समितियों में उन्होंने अपने आदमी बना लिये थे। केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके यहां दरबार लगाना पड़ता था। जानकी वल्लभ पटनायक और बिंदेश्वरी दुबे जैसे मुख्यमंत्रियों की कई बार उन्होंने प्राण-रक्षा की थी। मंत्रियों-मुख्यमंत्रियों को बनाने-बिगाड़ने लगे थे। जो जानकारियां, सूचनाएं उन्हें प्रधानमंत्री को यथावत, अविकल रूप में पहुंचानी चाहिए थीं, उन्हें फोतेदार अपनी और अपने 'आदमियों' की राजनीति के अनुसार बदल कर या विकृत करके पहुंचाते थे।

राजनीतिक अनुभव और कद में उनसे कहीं ऊंचे पार्टी नेता फोतेदार के यहां हाजिरी लगाने की अपमानजनक विवशता को स्वर देने लगे थे। फोतेदार को मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री निवास से दूर करके राजीव गांधी ने अपनी पार्टी के बहुमत की भावनाओं को सम्मान दिया है। इसका स्वागत हुआ है।

उस शाम कुछ अन्य घोषणाएं भी हुई थीं। उनमें दो काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला नारायण दत्त तिवारी को विदेश मंत्रालय से हटाकर वित्त और वाणिज्य मंत्रालय सौंपा जाना। दूसरा, शिव शंकर से वाणिज्य लेकर विधि तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालयों में भेजा जाना।

नारायण दत्त तिवारी का वित्तमंत्री बनना अपेक्षित था। वित्त, उद्योग, योजना—इन विषयों में पारंगत तिवारीजी विदेश विभाग में 'मिसफिट' थे। उद्योग क्षेत्र में उनकी साख का इससे अच्छा प्रमाण क्या होगा कि उनके वित्त और वाणिज्य मंत्री बनते ही बंबई तथा कलकत्ता स्टाक एक्सचेंजों में शेयरों के दामों में तेजी आ गयी। वित्त और वाणिज्य, इन दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक विभागों के एक साथ प्रमुख होने से तिवारी केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नंबर दो हो गये हैं।

शिव शंकर का वाणिज्य से हटकर विधि जैसे अमहत्वपूर्ण मंत्रालय में जाना कुछ आश्चर्यजनक था। कुछ दिन पहले ही स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद राजीव गांधी ने उन्हें गुजरात से राज्यसभा में फिर चुनवा लिया था। उसके पीछे भी शिवशंकर के मित्र फोतेदार का हाथ माना गया था। इसलिए फोतेदार

अब नंबर दो : नारायण दत्त तिवारी छाया : सुलेखा

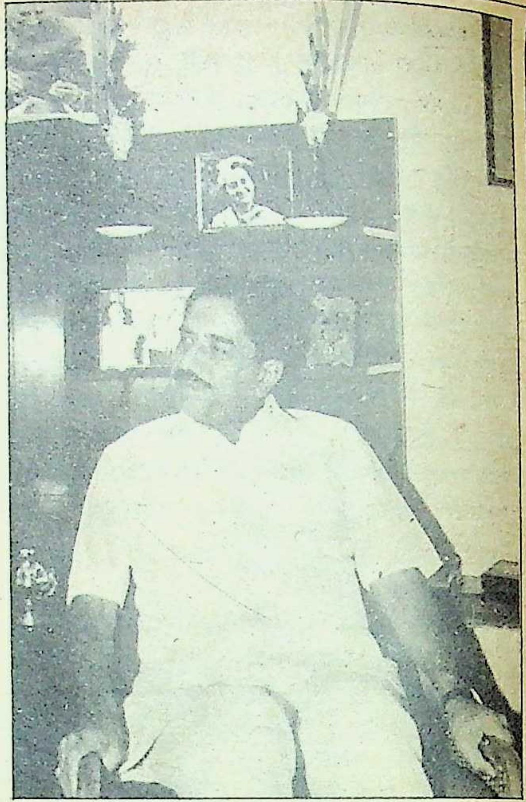

परदे के पीछे सक्रिय : आर०के० धवन

के हटने के साथ ही शिव शंकर की पदावनति को आपस में जुड़ा माना जा रहा है। यों, शिव शंकर के खिलाफ यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके एक ऐसी कंपनी को कुछ बड़े ठेके दिलवाये थे, जिसमें उनके पुत्र और एक अन्य संबंधी काम करते हैं।

फोतेदार के हटने का एक दूसरा गहरा आयाम और अर्थ भी है। माखन लाल फोतेदार के हटने के साथ ही राजीव गांधी के अल्पकालीन शासन का एक युग समाप्त हो गया है। जिन मित्रों-सलाहकारों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर होने के लिए राजीव गांधी की आलोचना होती रही है, उनमें फोतेदार अंतिम थे। उनसे पहले अरुण नेहरु, अरुण सिंह, अमिताभ-अजिताभ बच्चन सत्ता-शक्ति के बहुत ऊंचे शिखरों तक पहुंच कर गिर चुके हैं।

कैप्टन सतीश शर्मा अब भी प्रधानमंत्री निवास में बैठते हैं, लेकिन यह सर्वविदित है कि शिखर राजनीति में उनका हस्तक्षेप और भूमिका अब नगण्य है। वह राज्य सभा सदस्य अवश्य हैं, किन्तु शिखर राजनीति के हाशिए पर आ गये हैं। दो गैर-राजनीतिक मित्र जो अचानक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गये थे—रोमी चोपड़ा और मणि शंकर अय्यर-आज काफी समय से शांत और लगभग अदृश्य हैं।

राजीव गांधी राजनीति में संजय गांधी की मृत्यु से पैदा हुए शून्य को भरने के लिए लगभग अनिच्छापूर्वक इंदिरा गांधी द्वारा लाये गये थे। उनकी राजनीतिक शिक्षा आधी भी पूरी नहीं हो पायी थी कि श्रीमती गांधी की हत्या ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। वह राजनीति में कच्चे थे। उन्हें बैसाखियों की जरूरत थी, सतर्क और सक्षम हाथ-पैरों, आंख-कानों की जरूरत थी, ताकि असंख्य जटिलताओं से भरे भारतीय राजनीतिक अखाड़े में टिके रह सकें।

अपनी नितान्त अराजनीतिक मानसिक बनावट और पाश्चात्य जीवन शैली के कारण कांग्रेस के धोती-कुर्ता-धारी नेताओं, कार्यकर्ताओं से उनका सहज संवाद और संबंध नहीं बन पाया था। इस संवादहीनता ने उन्हें पारंपरिक कांग्रेसी नेताओं से दूर करके विवश किया कि अपनी बैसाखियों को उन लोगों में खोजें जो उनकी जैसी पृष्ठभूमि के हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं, उनके जीवन मूल्यों और शैली के करीब हैं।

ये बैसाखियां उन्हें मिलीं पुराने मित्रों, सहपाठियों सहयोगियों में। अरुण सिंह डेटाल बनाने वाली रेकिट कोलमैन कंपनी का मार्केटिंग निदेशक पद छोड़कर आ गये, सतीश शर्मा इंडियन एयरलाइंस से इस्तीफा देकर और अमिताभ बच्चन फिल्मों में अपने अतिव्यस्त जीवन में से काफी समय निकालने के लिए तैयार हो गये। इन तीनों की अंतिम जवाबदेही और सरोकार देश, पार्टी या किसी सिद्धांत से नहीं, एक व्यक्ति से था जो उनका मित्र था। अरुण नेहरू वहां उस परम विशिष्ट प्रभा मंडल में श्रीमती गांधी के समय से ही विद्यमान थे।

राजीव गांधी की अपार लोकप्रियता और संसद में अभूतपूर्व बहुमत—इन दोनों ने मिलकर इन मूलतः अराजनीतिक नव-राजनीतिज्ञों को एकाएक छत्रपतियों-सा निरंकुश बना दिया था। आरंभ में अरुण सिंह का जमाना था। माना जाता था कि पूरी राजीव सरकार वही चलाते हैं। उनकी पत्नी नीना सिंह सोनिया गांधी की विशिष्ट अंतरंग सखी थीं। दोनों परिवार साथ खाते-पीते, घूमते थे। दोनों के बच्चे साथ खेलते थे। अरुण सिंह का बंगला प्रधानमंत्री निवास से सटा हुआ था। धीरे-धीरे सोनिया-नीना और फिर राजीव-अरुण के संबंधों में ठंडक आने लगी। तब तक राजीव की दृष्टि मित्र की नहीं, शासक की हो गयी थी और कोई शासक किसी समान्तर सत्ता-केन्द्र को सहन नहीं करता।

फिर आया अरुण नेहरु का स्वर्ण-युग। वह कहने को तो ऊर्जा राज्यमंत्री और फिर बाद में गृहराज्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार, पार्टी के लिए मुख्य धन एकत्र करने वाले और पार्टी और सरकार की राजनीतिक नीतियों के प्रमुख सूत्रधार थे। १९८४ के चुनावों में टिकट वितरण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। और विपक्ष के दिग्गजों को हराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधव राव सिंधिया और बहुगुणा के लिए अमिताभ बच्चन को लड़ाने की सफल योजना उन्हीं के दिमाग की उपज थी। लेकिन धीरे-धीरे वह भी शायद अपने रिश्तेदार—नेता की इच्छा से अधिक शक्तिशाली हो गये थे। सूत्रों के अनुसार नेता से अधिक नेता की पत्नी को यह बात नागवार गुजर रही थी। इसलिए एक दिन वह भी अचानक सत्ता प्रतिष्ठान से बाहर हो गये और आज राजीव गांधी को अपदस्थ करने का संकल्प लिये उसका तानाबाना बुनने में व्यस्त हैं।

अमिताभ बच्चन के राजनीतिक उदय और अवसान की कहानी सबसे ताजी है इसलिए उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अरुण नेहरू व अरुण सिंह के विपरीत संसद से त्यागपत्र देने के बावजूद अमिताभ बच्चन राजीव के आज भी करीबी मित्र हैं।

अरुण नेहरू के हटने के बाद से फोतेदार की शक्ति कई गुना बढ़ गयी थी। तकनीकी रूप से उनका काम तो वही रहा जो पहले था, लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री के विश्वस्त व अंतरंग लोगों में अकेले वही रह गये थे, इसलिए वह धीरे-धीरे लगभग उस जगह पर आते जा रहे थे, जिस पर इंदिरा गांधी के जमाने में आर०के० धवन हुआ करते थे।

अब वह भी हट गये हैं। इसलिए जहां तक अंतरंग राजनीतिक सहायकों और सलाहकारों का संबंध है राजीव गांधी अब अकेले हैं। पिछले कई महीनों से रह-रह कर आर०के० धवन के वापस आने की खबरें उड़ती रही हैं। फोतेदार के मंत्री बनते ही बहुत से लोगों को यह संभावना एकदम प्रत्यक्ष-सी दिखने लगी। इसको बल मिला इस बात से कि ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने से विरत करने में धवन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। किंतु धवन की पुर्ननियुक्ति की कोई घोषणा नहीं हुई, तो खबरें छपने लगीं कि स्वयं धवन ने वापस आने से इनकार कर दिया था। वास्तविकता यह नहीं थी। एक जानकार सांसद ने 'माया' को बताया, "धवन से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। फोतेदार को यह धारणा दूर करने के लिए हटाया गया कि प्रधानमंत्री के चारों ओर गुटबाजी और उखाड़-पछाड़ करने वाले लोग हैं और प्रधानमंत्री उन्हें प्रश्रय देते हैं, इस मामले में तो धवन फोतेदार के गुरु माने जाते हैं। इसलिए इस मौके पर छोटे मैनीपुलेटर को हटा कर एक बड़े और ख्यात मैनीपुलेटर को बिठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

उपर से देखने में विचित्र स्थिति है। जब राजीव गांधी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं, वह एकदम अकेले हैं। विश्वस्त

मित्र-सलाहकारों-सहायकों के पुराने गुट की जगह उनके चारों ओर एक शून्य नजर आता है। यह शून्य और अकेलापन उन्होंने स्वयं चुना है। मित्रता और राजनीति के मिश्रण के दुष्परिणाम वह भोग चुके हैं। शायद यह भी समझ चुके हैं कि लोग और पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं उनको लड़ता और नेतृत्व करता देखना चाहते हैं, किसी शिखंडी की आड़ से बाण चलाने वाले सेनापति को नहीं।

इसे राजीव गांधी की परिपक्वता के रूप में भी देखा जा सकता है और उनकी विवशता के रूप में भी। एक केन्द्रीय मंत्री का 'माया' से कहना था कि उन्हें पिछले दिनों में यह देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता रहा है कि संकट के इस समय में राजीव गांधी पूरी तरह अविचलित, शांत और आत्मविश्वासपूर्ण रहे हैं। "मंत्रिमंडल की बैठकों में उनका पूरा व्यवहार बड़े सुखद आत्मविश्वास से भरा रहता है। वह विपत्तियों से घिरे किसी चिंतित व्यक्ति का आभास नहीं देते।" कोलंबो में सिंहली नौसैनिक के हमले में भी वह जितने अविचलित और शांत रहे, उसे दूरदर्शन पर देखने वाले सभी भारतीयों ने लक्षित किया और सराहा है। लेकिन अकेली इस ताजी परिपक्वता और आत्मविश्वास के सहारे राजीव गांधी वी०पी० सिंह और अरुण नेहरू की चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ने का निर्णय उनका अपना है, किंतु रणनीति बनाने में सहायता कर रहे हैं, उनके सचिव गोपीकृष्ण अरोड़ा, गृहमंत्री बूटा सिंह, नरसिम्हा राव, नारायण दत्त तिवारी और एक सीमा तक अर्जुन सिंह तथा नवल किशोर शर्मा।

सारी कांग्रेस पार्टी इस समय सितंबर की प्रतीक्षा कर रही है। सितंबर में, संभवतः दूसरे सप्ताह के बाद, आयेंगे वे परिवर्तन, घोषणाएं और कदम, जिनके सहारे राजीव गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह से लड़ेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल और कांग्रेस संगठन में व्यापक परिवर्तन होगा। कुछ ऐसी घोषणाएं की जायेंगी, कदम उठाये जायेंगे, जिनसे भारत की जनता को यह लगे कि इस सरकार का असली सरोकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों, भूतपूर्व राजाओं और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना नहीं, देश के दुर्बलतम और निर्धनतम को ऊंचा उठाना है। ये कदम क्या होंगे यह या तो अभी तक तय नहीं हुआ है या बहुत सफलतापूर्वक उन्हें गुप्त रखा जा रहा है।

संघर्ष दिनोंदिन गहरा रहा है। शुरू में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अचानक विपक्षी नेताओं से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया, तो पहले लोगों को लगा कि वह शायद अपने को दुर्बल महसूस करके विपक्ष से सहायता का हाथ मांगने गये हैं। तर्क यह भी था कि चन्द्रशेखर, बहुगुणा, हेगड़े जैसे प्रधानमंत्री पद के स्वयंभू दावेदार जब विपक्ष में पहले से ही बैठे हैं, तो राजासाहब को प्रधानमंत्री बनने के लिए मदद कौन देगा? यह भी कहा गया कि वी०पी० सिंह समझ गये हैं कि कांग्रेसियों का बहुमत उन्हें कभी समर्थन नहीं देगा, इसलिए वह मजबूरी में विपक्ष की ओर झुक रहे हैं। लेकिन स्थिति और वी०पी० सिंह गुट की रणनीति दोनों ही इतनी सरल नहीं हैं। आरिफ मोहम्मद खां का 'माया' से कहना था, "हम लोगों को पार्टी से निकले हुए पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, जबकि हम ढाई साल लड़ने की तैयारी में हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है।" सतपाल मलिक का कहना था, "हमारी यात्राओं का अनुभव यही है कि परिवर्तन की चाह में लोग हमसे आगे हैं, हम नहीं।" बंगलौर, हैदराबाद में वी०पी० सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ है। यह सच है कि दोनों जगह के गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की उसमें भरपूर मदद थी। उनके गुजरात दौरे ने भी काफी हलचल पैदा की है।

वी०पी० सिंह और उनके साथी अपना भावी आधार केवल कांग्रेसियों को ही मानकर नहीं चल रहे हैं। वे राजीव सरकार से जनता के मोहभंग और असंतोष को स्वर और स्वरूप देकर राजनीतिक दलों की सीमाओं से बाहर जाकर एक सर्वानुमति की तलाश में हैं। वह जानते हैं कि केवल जनसभाओं पर यह संघर्ष नहीं टिक सकता। इसे चलाने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा चाहिए। इस ढांचे की संरचना संभवतः १५ अगस्त तक स्पष्ट हो जायेगी। लोक संघर्ष समिति या जनसंघर्ष समिति जैसे नाम का एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जायेगा। पहले उसकी राज्य शाखाओं का गठन होगा और फिर जिला शाखाओं का। संगठन के कार्यकर्ताओं को आरंभ में अपेक्षाकृत छोटे कार्यक्रम दिये जायेंगे और धीरे-धीरे काम में तेजी लायी जायेगी।

राजनीतिक समुद्र-मंथन के इस दौर में शक्तियों और दलों के नये समीकरण बन रहे हैं। २४ विभिन्न युवा राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में राजधानी में एक सम्मेलन करके १९७४-७५ जैसा आंदोलन चलाने की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया है। उद्देश्य है वर्तमान सरकार को हटाना। सम्मेलन का एक अघोषित निर्णय यह भी था कि पहले यह संयुक्त आंदोलन खड़ा करके उचित समय पर उसे वी०पी० सिंह के आंदोलन से जोड़ दिया जायेगा जैसे १९७४ में संघर्ष समिति ने जयप्रकाश से जोड़ दिया था।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

राजीव गांधी

राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसा करते ही स्वार्थ और स्वहित का जो बंधन कांग्रेसियों को उनसे बांधे है, टूट जायेगा और तब राजनीतिक अराजकता में क्या स्थितियां बनेंगी, यह अस्पष्ट और अकल्पनीय है।

जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की सहायता करने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी अब राजीव सरकार को हटाने की मांग कर रही है। भाजपा, जनता पार्टी और वी०पी० सिंह लगभग एक स्वर में मध्यावधि चुनावों की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस-शासित प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन की मांग जोर पकड़ रही है। उ० प्र० में २२ हरिजन कांग्रेसी विधायकों ने वीर बहादुर सिंह के खिलाफ अगस्त के प्रथम सप्ताह में वक्तव्य जारी किया और वी०पी० सिंह से जुड़ने की घोषणा की है। हरिजन विधायकों का यह खुला विद्रोह पार्टी को महंगा पड़ेगा। गनीखान चौधरी और मुफ्ती मोहम्मद सईद बगावत की मुद्रा में हैं, इससे रहे-सहे मुस्लिम समर्थन से राजीव और हाथ धो बैठ सकते हैं।

ऐसे में राजीव गांधी की रणनीति जो अब तक खुली है, बहुत उत्साहजनक नहीं है। इस समय लड़ाई विधायकों और सांसदों के अंकगणित से बाहर वहां जा चुकी है, जहां निर्णय जनता-जनार्दन में शासक और उसको चुनौती देने वाले विद्रोही की तुलनात्मक छवियों पर होगा। जनता की दृष्टि अब निर्णायक होगी।

राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसा करते ही स्वार्थ और स्वहित का जो बंधन कांग्रेसियों को उनसे बांधे है, टूट जायेगा और तब राजनीतिक अराजकता में क्या स्थितियां बनेंगी, यह अस्पष्ट और अकल्पनीय है। इस समय उनकी और उनकी सरकार के खिलाफ जनरोष में उनकी पुनर्विजय लगभग असंभव है। इसलिए यह जोखिम राजीव गांधी नहीं उठा सकते।

किंतु समय यह जोखिम उठाने का ही है। पारंपरिक, घिसे-पिटे उपायों के सहारे इस तूफान से निकलने की आशा मूर्खतापूर्ण है। राजीव गांधी ने दिसंबर १९८६ में पार्टी से भ्रष्टाचारियों, सत्ता के दलालों को निकाल फेंकने का संकल्प किया था। हुआ उसका उलटा। अब समय है उस संकल्प को मूर्त करने का। भ्रष्ट-धूमिल छवि वाले मुख्यमंत्रियों को बदलें। पार्टी संगठन और सरकार में अनुभव और छवि के लोगों को लायें। भले ही इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े, देश को फिर समाजवाद के रास्ते पर लायें और निर्धन, निर्बल से अपना सरोकार प्रमाणित करें, लोग राजीव गांधी से यही चाहते हैं।

यह होना चाहिए उनका प्रत्याक्रमण—सकारात्मक, ठोस और साहसपूर्ण। इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह को देश में अस्थिरता लाने के षड्यंत्र का औजार बताने से आक्रामक मुद्रा बन सकती है, प्रतिद्वंद्वी घायल नहीं होता।

—राहुल देव

संसद में बोफोर्स

समय पर मानसून न आने से जितनी गर्म थी दिल्ली, उससे कहीं अधिक गर्म माहौल था संसद का मानसून सत्र-विपक्ष को बोफोर्स पर बहस की अनुमति मिलने के कारण सत्र के दूसरे दिन २८ जुलाई को अपनी पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत राज्यसभा में जनता पार्टी के गुरुपदस्वामी, मार्क्सवादी पार्टी के दीपेन घोष व अन्य विपक्षी सांसदों के नेतृत्व में १३ सांसदों ने तथा लोकसभा में जनता पार्टी नेता मधु दंडवते के नेतृत्व में १५ सांसदों ने बोफोर्स प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बहस के लिए प्रश्नकाल से ही सरकार पर दबाव बनाये रखा। दोनों सदनों में विपक्ष चाहता था प्रश्नकाल स्थगित करके विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बहस हो। किसी भी सदन में इसकी अनुमति न मिलने पर विपक्ष के हो हल्ले ने हंगामे का माहौल बना दिया। कई बार स्थिति यह हो गयी कि उत्तेजित प्रतिपक्षी सांसद संसदीय नियमों और गरिमा के प्रतिकूल अध्यक्ष और सभापति की कुरसी के सामने वाली खाली जगह पर, जिसे अंग्रेजी में 'वेल आफ द हाउस' (सदन का कुआं) कहा जाता है, धरना देकर बैठ गये।

"विशेष परिस्थितियों में प्रश्नकाल स्थगित किया जा सकता है।" ऐसे नियमों का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों ने सभापति और अध्यक्ष को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर सरकारी पक्ष ने इसे नजरअंदाज करते हुए संसदीय कार्यवाही जारी रखने का प्रयास किया जो विपक्ष के हंगामे के कारण संभव नहीं हो सका। अंततः अलग-अलग समय पर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। राज्यसभा में विपक्ष का व्यवहार तो हंगामें और शोरशराबे तक ही सीमित रहा, किंतु लोकसभा में मार्क्सवादी पार्टी के अजय विश्वास द्वारा रक्षामंत्री के०सी० पंत के हाथ से दस्तावेज छीन लेने के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गयी।

अगले दिन २९ जुलाई को बोफोर्स पर विशेषाधिकार की जगह सत्तापक्ष द्वारा अजय विश्वास के निलंबन के लिए लाया गया प्रस्ताव लोकसभा में छाया रहा। दोनों ओर से अजय विश्वास के निलंबन के विरोध व समर्थन के बाद अजय विश्वास को पूरे सत्र की अवधि के लिए सदन से निलंबित किये जाने का निर्णय सुना दिया गया। हालांकि उन्होंने पिछले दिन की गलती के लिए सदन से लिखित माफी भी मांग ली थी। निलंबन की घोषणा के साथ ही सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गयी। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही तेलुगु देशम के सदस्य राधाकृष्ण द्वारा, राजीव गांधी सीआईए एजेंट हैं' की आपत्तिजनक पट्टी सदन में लहराने के कारण स्थगित कर दी गयी। राधाकृष्ण को इसके लिए राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया।

२९ जुलाई को लोकसभा में अजय विश्वास के निलंबन की मांग को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा दी गयी दलीलें न तो तर्कसंगत थीं और न ही तथ्यों पर आधारित। अजय विश्वास का लिखित माफी नामा मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के इस मामले को खतम करने के अनुरोध की उपेक्षा करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें दंडित करने की मांग बरकरार रखी। ऊर्जामंत्री बसंत साठे ने १९७८ में श्रीमती इंदिरा गांधी की सदन से बर्खास्तगी का उल्लेख करते हुए यह गलत बयानी की कि श्रीमती गांधी को अपनी गलती की माफी मांग लेने पर भी दंडित किया गया।

लोकसभा कार्यवाही में दर्ज है कि इंदिरा गांधी ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था। इस मामले में सरकारी पक्ष द्वारा लाये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात तत्कालीन अध्यक्ष ने फैसला सुनाया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेषाधिकार समिति के सामने गलतबयानी कर सदन को गुमराह किया था। श्रीमती गांधी को समिति के सामने शपथ लेने से इनकार करने के कारण भी दोषी माना गया था। इतना ही नहीं, १६ जून, १९७८ को श्रीमती गांधी द्वारा समिति के सामने दिये गये बयान में भी गलत बातें पायी गयी थीं। इस आधार पर सदन की अवमानना के आरोप में चिकमंगलूर से जीतकर आयीं श्रीमती गांधी और उनके सहयोगी आर०के० धवन व सीबीआई के पूर्व निदेशक डी० सेन को सदन ने दोषी करार दिया था। इसी अपराध के कारण सदन ने श्रीमती गांधी की सदस्यता भंग करने और कुछ दिन के लिए जेल भिजवाने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि सदन द्वारा सजा दिये जाने के बाद उनके कई साथियों ने सदन का सदस्य न होने पर भी सदन में प्रवेश कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचायी थी।

बोफोर्स प्रकरण के हंगामें में सदन के माननीय सदस्यों—विशेषकर कांग्रेसी सदस्यों की मानसिकता का पता ३० जुलाई को उस समय चला, जब श्रीलंका से प्रधानमंत्री की वापसी के बाद श्री भगत ने यह कहकर निलंबन आदेश वापस लेने संबंधी प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाहते हैं कि यह अध्याय यहीं समाप्त कर दिया जाये। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रजातंत्र में संसद के किसी सदन का सभापति या अध्यक्ष सरकार और प्रतिपक्ष से बड़ा होता है। लेकिन एच०के०एल० भगत ने लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ की अध्याय समाप्त करने की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जबकि प्रधानमंत्री के कहने पर अपने

द्वारा रखे गये निलंबन प्रस्ताव के निर्णय के स्थान पर निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव भी रख दिया।

वैसे १९ दिसंबर, १९७८ को सदन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को जेल भिजवाना संसदीय इतिहास की पहली घटना थी और २० जुलाई, १९८७ को एक विपक्षी सदस्य द्वारा मंत्री के हाथ से कागज छीनने की घटना भी पहली ही है। साथ ही यह भी पहली बार हुआ कि एक सप्ताह में चार दिन लगातार संसद के दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित किये गये। दिवंगतों को श्रद्धांजलि या प्रधानमंत्री के ऊपर हत्या के इरादे से किये गये हमले से सदन का स्थगन परिस्थितिजन्य और समय सापेक्ष है, लेकिन किसी विषय विशेष को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर स्थगन की विपक्षी रणनीति और सत्ता पक्ष द्वारा उस विषय पर बहस की अनुमति न देने का दृढ़ निश्चय ही इस ऐतिहासिक स्थगन का मूल कारण रहा, जिसका केन्द्र बिन्दु था बोफोर्स।

दो दिन तक सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान आने के बाद राज्यसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। जिसमें विपक्ष की तीन मांगें स्वीकार कर ली गयीं। एक-सरकार विपक्ष द्वारा प्रस्तावित बोफोर्स प्रकरण पर आधे घंटे की चर्चा का अवसर देगी। दो-उपसभापति प्रतिभा पाटिल विपक्षी सदस्यों के पिछले दिन के आदेश में संशोधन करेंगी तथा तीसरा—तेलुगु देशम सदस्य राधा कृष्ण के लिखित माफी मांगने पर उनका निलंबन वापस ले लिया जायेगा।

उल्लेखनीय है बोफोर्स प्रकरण पर सप्ताह पर्यन्त विपक्ष द्वारा लिये गये बहिष्कार के निर्णय की नौबत ही नहीं आती, अगर विपक्ष ने संसद के पिछले सत्र में २० अप्रैल को तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह द्वारा बोफोर्स मामले पर दिये गये तीन पृष्ट के बयान को गंभीरता से लिया होता। इस बयान में अरुण सिंह ने कहा था कि भारतीय थल सेना के आधुनिकीकरण की नीति के तहत आधुनिक अस्त्र खरीदने का निर्णय लिया गया था। ऐसी बंदूकें, जिनकी न्यूनतम मारक क्षमता २५ कि०मी० हो तथा अतिरिक्त उपकरण लगाने पर मारक क्षमता ३० कि०मी० तक हो, खरीदने के लिए एक दर्जन विदेशी कपनियों से आंवेदन पत्र मिले। जिनमें मोफना (फ्रांस), बोफोर्स (स्वीडन), आईएमएस (ब्रिटेन) और एल्पाइंस (आस्ट्रिया) चार कंपनियों के आवेदनों पर ही विचार किया गया तथा अंत में केवल बोफोर्स की निविदा को स्वीकृति मिली।

बंदूकों की खरीद के लिए बनी समिति में रक्षा सचिव, रक्षा उत्पादन सचिव, व्यय सचिव तथा उपसेनाध्यक्ष सदस्य थे। इन्होंने बोफोर्स के नाम पर सहमति व्यक्त की। स्वीडन की कंपनी से बातचीत में यह स्पष्ट किया गया था कि बंदूकों की खरीद में कोई बिचौलिया नहीं होगा। बिचौलिये की स्थिति में करार तोड़ा जा सकता है।

तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री के संसद में दिये गये बयान में यह साफ-साफ कहा गया था कि बोफोर्स कंपनी ने बताया था कि उसकी एक भारतीय फर्म को होटल में रहने की व्यवस्था, परिवहन तथा दूरसंचार की सेवाओं का काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था। उस समय प्रतिपक्ष के सांसदों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि पूरक प्रश्न के रूप में वे यह पूछ सकते थे कि बोफोर्स कंपनी द्वारा किराये पर ली गयी भारतीय कंपनी कौन थी? क्या उस कंपनी ने कागजों पर सौंपे गये काम के अलावा भी कोई काम किया? साथ ही विपक्ष यह भी जान सकता था कि बारह कंपनियों में केवल चार कंपनियों को ही क्यों चुना गया? उस पर भी बोफोर्स को ही ठेका क्यों दिया गया? और क्या वास्तव में बोफोर्स की निविदा सबसे कम रकम वाली थी? प्रश्न पूछने के अधिकार के तहत विपक्ष सदन में अन्य कंपनियों के निविदा-विवरण की मांग भी कर सकता था। किंतु इसके ठीक विपरीत विपक्ष विन चड्ढा के घर की तलाशी की प्रतीक्षा में रहा। यदि उस समय यह सारी जानकारी विपक्ष ने मांग ली होती, तो आज प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बहस की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती।

संसदीय नियमों के अनुकूल विपक्ष द्वारा लाये गये किसी प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न दिया जाना संख्या के बल से समर्थ सरकारी पक्ष की आंतरिक कमजोरी का प्रतीक है। इस मामले में सरकारी पक्ष संसदीय जांच समिति का गठन करके कम-से-कम आने वाले तीन-चार माह तक इस मामले की चर्चा से पिंड छुड़ाना चाहता है। क्योंकि एक बार मामला जांच समिति को सौंपे जाने के बाद, जब तक जांच समिति रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक इस विषय पर संसद में किसी भी प्रक्रिया के तहत न तो प्रश्न पूछा जा सकता है, न चर्चा ही की जा सकती है।

> संसदीय नियमों के अनुकूल विपक्ष द्वारा लाये गये किसी प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न दिया जाना संख्या के बल से समर्थ सरकारी पक्ष की आंतरिक कमजोरी का प्रतीक है। इस मामले में सरकारी पक्ष संसदीय जांच समिति का गठन करके कम-से-कम आने वाले तीन-चार माह तक इस मामले की चर्चा से पिंड छुड़ाना चाहता है। क्योंकि एक बार मामला जांच समिति को सौंपे जाने के बाद, जब तक जांच समिति रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक इस विषय पर संसद में किसी भी प्रक्रिया के तहत न तो प्रश्न पूछा जा सकता है, न चर्चा की जा सकती है।

इस गर्म माहौल के बहुचर्चित नेता और पूर्व मंत्री कमलाकान्त तिवारी को जनता पार्टी के प्रो० मधु दंडवते के लिए अपशब्दों के प्रयोग के कारण अध्यक्ष ने सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। अध्यक्ष द्वारा श्री तिवारी से अपने शब्द वापस लेने अथवा सदन से बाहर चले जाने के लिए कहे जाने के बाद भी उन्होंने अपने शब्द वापस लेने से इनकार किया और यह कहकर कि वह "विरोधस्वरूप सदन से बाहर जा रहे हैं," बाहर चले गये। मजे की बात यह है कि संसदीय गरिमा का दम भरने वाले अनेक कांग्रेसी सदस्य अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद श्री तिवारी को प्रोत्साहित कर रहे थे। इसके ठीक विपरीत विपक्ष के बहिष्कार के कारण राज्यसभा बिना विपक्ष के अपना काम निपटाती रही। अनुकूल वातावरण के कारण राज्यसभा में कांग्रेसी सदस्यों की उपस्थिति भी बहुत कम रही।

४ अगस्त को लोकसभा में कांग्रेस-स के के०के० उन्नीकृष्णन ने दावा किया कि १९८० के बाद हर रक्षा सौदे में कमीशन लिया गया है। उनके पास इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। उन्होंने कहा यदि रक्षामंत्री चाहें, तो वह इस संबंध में सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी ओर राज्यसभा में गृहमंत्री बूटा सिंह ने आतंकवादियों और विघटनकारी शक्तियों—विशेषकर अमरीकी गुप्तचर संस्था सीआईए—की गतिविधियों की, देश की एकता अखण्डता के लिए, गहराई से जांच कराने का मुद्दा उठाया।

लोकसभा में इस बहस के बाद रक्षामंत्री के०सी० पंत और संसदीय कार्यमंत्री एच०के०एल० भगत ने विपक्षी नेताओं को अलग वार्ता के लिए आमंत्रित किया। ४५ मिनट की यह बैठक एच०के०एल० भगत के मुताबिक असफल रही, मगर वार्ता का दौर ईद के दिन भी जारी रहने का उन्होंने संकेत दिया।

ऐसे अनिश्चयात्मक माहौल में विपक्ष की ओर से दो नये प्रस्ताव आ रहे हैं। एक है लोकदल अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा का। उन्होंने सुझाव दिया है कि सर्वोच्च न्यायपालिका के अवकाशप्राप्त तीन जजों, सेना के अवकाश प्राप्त ब्रिग्रेडियर अथवा उससे उच्च पद के दो हथियार विशेषज्ञ अधिकारी और कोस्ट एकाउंटेंट आदि के साथ एक नागरिक जांच समिति बनाकर बोफोर्स प्रकरण की जांच की जाये। अपने तर्क के समर्थन में श्री बहुगुणा का कहना है कि जलियांवाला बाग की जांच किस सरकारी आयोग ने की थी? जनता जिसे स्वीकार करे, उसी समिति की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर विपक्षी सांसद अपनी अलग समिति बनाकर इस मामले की जांच करने पर भी विचार कर रहे हैं।

कांग्रेस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले व्हिप भी जारी किया। उनका इरादा बोफोर्स जांच समिति के व्हिप की आड़ में यह था कि या तो विद्रोही इंका सांसद इस प्रश्न पर उनका समर्थन करें वरना अपनी सदस्यता से हाथ धोयें। कुल मिलाकर बोफोर्स कांग्रेस के गले की हड्डी बना हुआ है। देखना है कांग्रेस और उसकी सरकार इस समस्या से किस तरह निपटती है।

—दिलीप कुमार

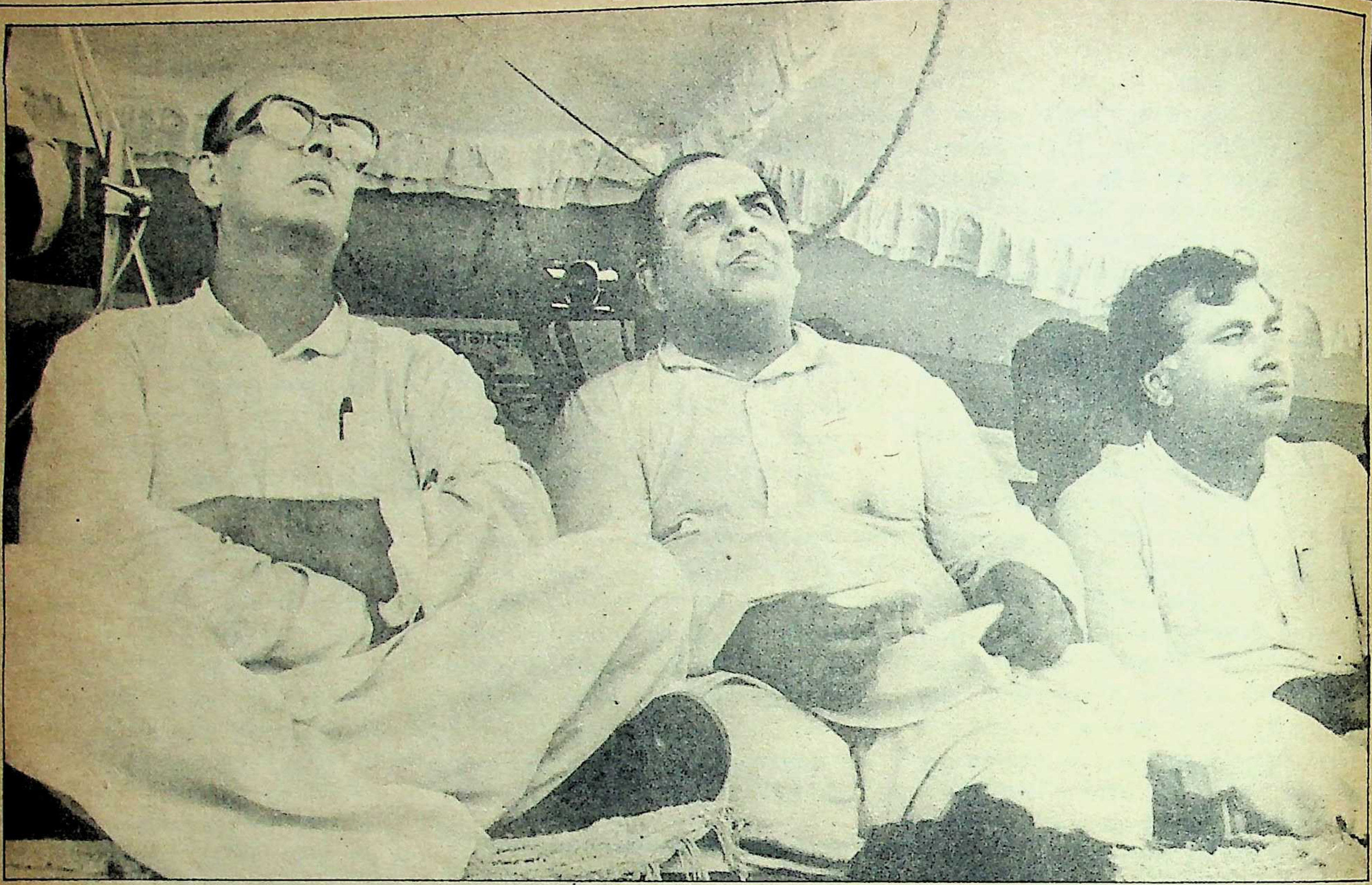

विपक्ष के मैदान पर हावी : वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां

वी०पी० सिंह और विपक्ष

वी०पी० सिंह केवल सत्तारूढ़ दल के लिए ही चुनौती नहीं बन गये हैं, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी समस्या बन गये हैं। सारे विपक्षी दल राजीव गांधी के विरुद्ध उनके स्वर-में-स्वर मिलाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उनका राजनीतिक रिश्ता क्या हो—इस सवाल का अभी वे उत्तर नहीं तलाश कर पाये हैं। स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अभी कोई नयी पार्टी बनाने या किसी दल में शामिल होने से इनकार किया है। वी०पी० सिंह और विपक्ष के अपरिभाषित रिश्ते की पहेली का हल तलाश रहे हैं—**पुनीत टंडन**

"हम विश्वनाथ प्रताप सिंह से हाथ मिलाने को तैयार हैं, पर उन्हें गले लगाने को नहीं"—भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी राजधानी में पत्रकारों को बता रहे थे।

विश्वनाथ प्रताप सिंह से हाथ मिलाने की तत्परता और उनसे गले मिलने में परहेज की इस दुविधापूर्ण स्थिति में न केवल भारतीय जनता पार्टी सतर्कतापूर्ण अपनी रणनीति खोजने में लगी है, बल्कि लगभग सभी विपक्षी दल 'राजा मांडा' और उनके भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के साथ अपने संभावित संबंधों को परिभाषित करने की कसरत में जुटे हैं।

एक हाथ में तिरंगा और दूसरा हाथ विपक्ष की ओर बढ़ाये विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय राजनीति में एक उलझी हुई गुत्थी बन चुके हैं। उनकी बंद मुट्ठियों में राजीव सरकार को 'भ्रष्ट' और 'बेईमान' सिद्ध करने वाले तथ्यों की एक कथित लंबी फेहरिस्त छुपी है और दूसरी तरफ भावी रणनीति भी। एक अत्यन्त सतर्क और सुविचारित ढंग से वह धीरे-धीरे अपनी मुट्ठियां उतनी ही खोल रहे हैं, जिससे केवल उतना ही दिख सके, जितना वह चाहते हैं। शेष अभी अस्पष्ट है—विश्वनाथ प्रताप सिंह की रणनीति और उसी के साथ विपक्षी दलों से उनका रिश्ता।

यही कारण है कि आज विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के लिए किसी भी विपक्षी दल या नेता के मुकाबले ज्यादा खतरनाक चुनौती बने हुए हैं, वहां दूसरी तरफ वह विपक्षी दलों की आशा का केन्द्र बिन्दु भी बने हुए हैं—और चिन्ता का कारण भी। आशा का बिन्दु इसलिए कि संसद में अपार बहुमत की स्वामी राजीव सरकार को पिछले ढाई वर्षों में जो चुनौती सारे विपक्षी दल मिलकर नहीं दे पाये, वह काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गत ढाई महीनों में कर दिखाया है।

सहर्ष समर्थन: हेगड़े

वी०पी० सिंह पर सशंक नजर: चंद्रशेखर

यही कारण है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने और फिर निकाले जाने के पहले ही से विपक्षी नेताओं की आंखों में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति दोस्ताना भाव नजर आने लगे थे। इसका अर्थ यह नहीं कि एक वर्ष पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के बजट के खिलाफ भारत बंद के आयोजक और गिरफ्तारियां देने वाले विपक्षी नेता यह भूल चुके हैं कि उन्होंने ही 'राजा मांडा' के दहिया तथा रामजानकी ट्रस्ट के कथित घोटालों की लम्बी सूची उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पेश की थी। मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में वी०पी० सिंह द्वारा चलाये गये दस्यु-विरोधी मुहिम में हजारों बेगुनाह हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के लोगों की पुलिस द्वारा कथित हत्या की सूचियां भी इन्हीं विपक्षी नेताओं ने तैयार की थीं। राजीव सरकार की आर्थिक नीतियों को जी भर कर कोसने वाले भी यही नेता हैं, जिसके निर्माण तथा क्रियान्वयन में वित्तमंत्री के रूप में मुख्य भूमिका विश्वनाथ प्रताप सिंह की ही थी।

ज्यादा महत्वपूर्ण बात : लेकिन मंत्रिमंडल के बाद कांग्रेस से भी निकाले जाने के फौरन बाद तमाम विपक्षी नेताओं के लिए तात्कालिक महत्व का मुद्दा वी०पी० सिंह का अतीत या राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल विश्वनाथ प्रताप सिंह उनके राजनीतिक 'शत्रु' के सबसे बड़े 'शत्रु' हैं। इस रिश्ते से देवीलाल, बीजू पंटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, एन०टी० रामाराव जैसे कई विपक्षी नेताओं को वी०पी० सिंह में एक 'राजनीतिक मित्र' की छवि नजर आने लगी। जहां एक तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर पर उनके कांग्रेसी समर्थकों व असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं की भीड़ जुटने लगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं से उनकी लम्बी मुलाकातों का दौर भी तेज होता गया।

कांग्रेस से बाहर आने के एक हफ्ते के अन्दर ही विश्वनाथ प्रताप सिंह विभिन्न विपक्षी दलों के लगभग एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय नेताओं से लम्बी राजनीतिक मंत्रणाएं कर चुके हैं। दोनों ही पक्ष पूरी सर्तकता, पर गर्मजोशी के साथ जहां आपस में हाथ मिला रहे हैं वहीं एक दूसरे की सीमाओं व स्थितियों को तौल भी रहे हैं। इसी प्रक्रिया में धीरे-धीरे विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वह विपक्ष के अंतर्विरोधों को भी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तक दक्षिण पंथ से वामपंथ तक दो विपरीत ध्रुवों के मध्य छितराये विभिन्न विपक्षी दलों में, किसी एक ध्रुव के नजदीक खड़े होकर रह जाने के खतरे से वह वाकिफ हैं। उनके सामने यह सवाल है कि भाजपा तथा कम्युनिस्ट दोनों काडर आधार वाले दलों के कठोर सैद्धांतिक तथा संगठनात्मक ढांचों में उनके लिए कोई स्थान कतई संभव नहीं है। संभव है तो सिर्फ दोस्ताना संबंधों की सीमित भूमिका। वह भी समान सोच के कुछ मुद्दों पर साथ-साथ संघर्ष तक।

ऐसी स्थिति में दोनों लोकदल, जनता पार्टी, कांग्रेस-स, तेलुगुदेशम जैसे मध्यममार्गी दलों में विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसे अनेक नेता नजर आये, जिनसे वह अपने आपको कांग्रेसी कहते हुए भी बात करने में सुविधा महसूस करते हैं। रामकृष्ण हेगड़े, देवीलाल, के०पी० उन्नीकृष्णन आदि ऐसे ही नेता हैं जिनसे कांग्रेस से निकाले जाने के तुरन्त बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भेंट की।

बन्द कमरों में होनेवाली इन मुलाकातों में विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह स्पष्ट हो गया होगा कि जहां एक तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के क्षेत्र या प्रदेश विशेष तक सीमित जनाधारवाले नेताओं से समर्थन पाना सरल है, वहां व्यापक पहचान और उत्तुंग महत्वाकांक्षा वाले राष्ट्रीय नेताओं से समर्थन पाना मुश्किल है। शायद इस बात को वह समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनसे संवाद भी स्थापित न करें। इसी प्रक्रिया में अपनी बातचीत के दूसरे दौर में उन्होंने जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर से उनके भोंडसी स्थित भारत यात्रा केन्द्र में जाकर दो घंटे से ज्यादा समय तक लम्बा विचार-विमर्श किया।

चन्द्रशेखर तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह की यह मुलाकात दोनों ही पक्षों के लिए लाभदायक और आवश्यक है। इसके बाद जहां एक तरफ जनता नेता का यह भय दूर हुआ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कहीं रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक आदि उनके दल के नेताओं के साथ मिलकर कोई ऐसा समीकरण तो नहीं खड़ा करने जा रहे जो चन्द्रशेखर के लिए नागवार साबित हो। वहीं दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए भी यह जरूरी था कि वह विरोधी दलों के आंतरिक

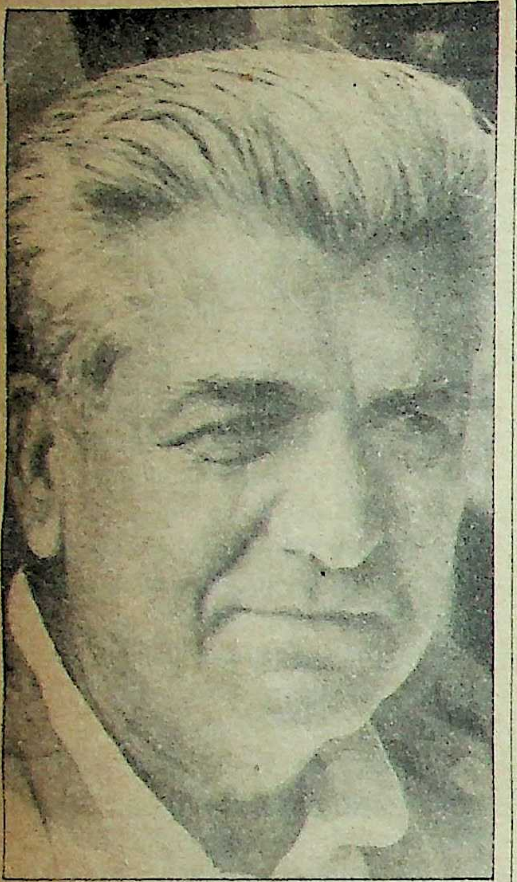

सशर्त समर्थन: देवीलाल

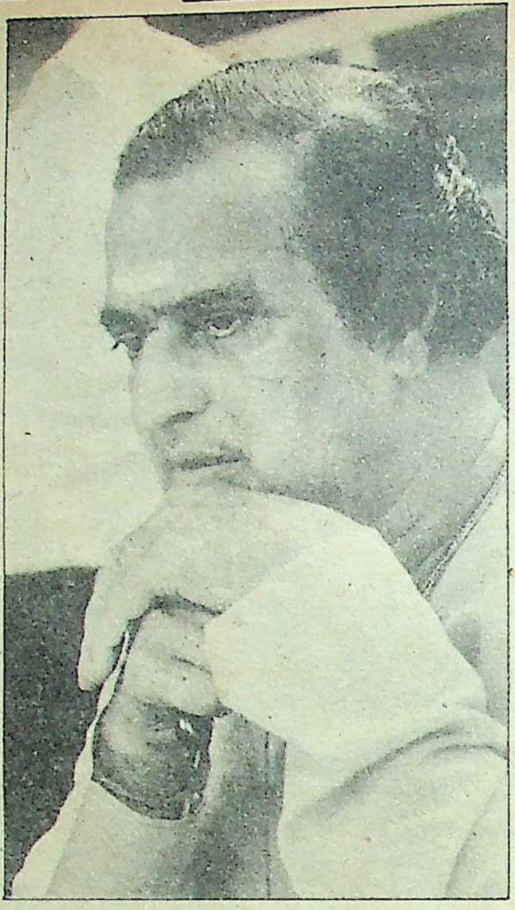

मुहीम में साथ: एन०टी०आर०

कलह की छाया अपने ऊपर न पड़ने दें तथा किसी एक गुट विशेष का समर्थन पाने के चक्कर में दूसरे गुट को अपना शत्रु न बना बैठें। भोंडसी की इस मुलाकात के बाद दोनों ही पक्षों को इस दिशा में लाभ हुआ। इससे पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह की विपक्षी नेताओं से हुई मुलाकातों के दौरान राजधानी के राजनीतिक हलकों में इस अटकल ने भी ज़ोर पकड़ा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह असंतुष्ट कांग्रेसियों, चन्द्रशेखर-विरोधी खेमे के जनता नेता रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक, लोकदल में देवीलाल तथा विभिन्न छोटे-छोटे संगठनों को मिलाकर एक राजनीतिक संगठन का तानाबाना बुन रहे हैं। लेकिन बाद में जब मुलाकात करने वाले नेताओं ने यह ब्यौरा दे दिया कि उनके और वी०पी० सिंह के बीच क्या बातें हुई हैं, तो यह संभावना क्षीण हो गयी।

वी०पी० सिंह से मुलाकात के बाद देवीलाल ने लोकदल की बैठक में बहुगुणा सहित सभी नेताओं को विस्तार से बताया कि वह राजा मांडा को क्या सलाह देकर आये हैं और उनके दल की क्या भूमिका होनी चाहिए। देवीलाल का कहना था, "मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से साफ कहा कि पहले तो तुम अपना यह कांग्रेस का चक्कर छोड़ो और सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाने का प्रयास करो, जिसके द्वारा पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा जा सके।" इसी के साथ देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति अपनी टिप्पणी भी लोकदल नेताओं के सामने पेश की: "अभी वह कुछ कच्चा पड़ रहा है, न तो वह कांग्रेस के चक्कर से मुक्त हो पाया है और न ही विपक्षी दलों के प्रति अपनी नजर साफ कर पाया।"

देवीलाल विश्वनाथ प्रताप सिंह को पूरा समर्थन देने को तैयार हैं, बशर्ते वह सभी विपक्षी दलों का एक साझा मोर्चा बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करें। किंतु लोकदल का एक बड़ा वर्ग तथा बहुगुणा-समर्थकों को इसमें अभी हिचक है। उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियां ही लोकदल का मुख्य आधार हैं। यह वर्ग अभी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में डकैती-उन्मूलन अभियान के तहत होने वाली मुठभेड़ों को पूरी तरह से भूल नहीं पाया है। लोकदल के एक नेता का कहना था, "उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार उस समय और मजबूत हुआ था, जब लोकदल ने झूठी पुलिस मुठभेड़ों के खिलाफ पुरजोर मुहीम चलायी थी।" वह उन दिनों की याद दिला रहे थे, जब मुलायम सिंह यादव महीनों सिर्फ इसी एक काम में लगे हुए थे कि बदायूं, इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रूखाबाद, आगरा, अलीगढ़, उन्नाव, बाराबंकी आदि जिलों से रोज आने वाले तारों का गट्ठर बनाकर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तथा पुलिस महानिदेशक को दिया करते थे। ये तार अधिकतर पिछड़ी जातियों के उन ग्रामीणों के हुआ करते थे, जिन्हें यह भय होता था कि कहीं उनके क्षेत्र का दरोगा उनको फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार न दे। आज उन्हीं पिछड़ी जातियों के नवयुवक उत्तर प्रदेश में लोकदल के सबसे मजबूत काडर हैं।

बहुगुणा का रुख: इसी प्रकार हेमवती नंदन बहुगुणा के एक समर्थक नेता का तर्क था कि पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त लोकदल का प्रभाव बहुगुणाजी के प्रयासों से मुसलमानों तथा हरिजनों में भी पिछले तीन-चार वर्षों में काफी बढ़ा है। क्या मुसलमान-आधार ऐसे विश्वनाथ प्रताप सिंह को स्वीकार कर लेगा, जिनके दायीं तरफ बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं को कब्जा दिलवाने वाले अरुण नेहरू तथा बायीं तरफ मुस्लिम बिल का विरोध करने वाले आरिफ मोहम्मद खां हैं जो सांप्रदायिकता-विरोधी होने के कारण कट्टरपंथियों की नजर में 'काफिर' हैं। फिलहाल स्वयं हेमवती नंदन बहुगुणा इस मामले पर अपने कान व आंख पूरी सतर्कता के साथ खुले रखते हुए मुंह बंद किये हुए हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार व सत्ता के केन्द्रीयकरण के खिलाफ जो आवाज आज विश्वनाथ प्रताप सिंह उठा रहे हैं, उस आवाज को आज से सात वर्ष पहले उन्होंने तब उठाया था, जब कांग्रेस में राजीव गांधी जैसा कमजोर नेता नहीं, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी अत्यन्त शक्तिशाली नेता मौजूद थीं। बहुगुणा के एक समर्थक का कहना था कि बहुगुणा कांग्रेस में काले धन, भ्रष्टाचार, अलोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाते हुए श्रीमती गांधी को हर दूसरे दिन पत्र लिख रहे थे और सभी मुद्दे लगभग सभी कांग्रेसी नेताओं—जिनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह भी शामिल थे—तक पहुंचा रहे थे, तब राजा मांडा की अंतरात्मा क्यों नहीं जगी? इसी के साथ वह यह भी बताना नहीं भूलते हैं कि जब बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के आदेश के विरुद्ध जहां एक तरफ घनश्याम दास बिड़ला को राज्यसभा में नहीं जाने दिया था, वहीं दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण को राजकीय अतिथि घोषित किया था। फिर कांग्रेस छोड़ने के साथ ही बहुगुणा ने लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ी थी और दुबारा चुनाव लड़कर लोकसभा तक आये थे। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसा करेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में क्या उनकी ऐसी ही भूमिका थी? बहुगुणा-समर्थक ऐसे ढेर सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन स्वयं हेमवती नंदन बहुगुणा फिलहाल विश्वनाथ प्रताप सिंह पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं लगाते। "माया' से इस संदर्भ में उनका केवल इतना ही कहना था, "विश्वनाथ प्रताप सिंह देर आये दुरुस्त आये, एक बार उन्हें यह तो कहना ही चाहिए कि अब तक मैं जिस दल या राजनीति में था, वह भ्रष्ट थी, गलत थी। फिर जहां एक बार आपने प्रायश्चित की गंगा में गोता लगा लिया, तो देश की जनता सब माफ कर देती है। फिर आइए हम सब साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, हम सब सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है।"

अजीत सिंह की झिझक: लोकदल (अजीत सिंह) की विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति झिझक को और भी साफ समझा जा सकता है। यद्यपि इस बीच लोकदल-अ के अध्यक्ष अजीत सिंह तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मध्य संपर्क हो चुका है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। अजीत सिंह की चिन्ता का मुख्य कारण थीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्राएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अजीत सिंह अपना गढ़ मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यह नागवार गुजरना स्वाभाविक है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बिना उन्हें विश्वास में लिये, पहले हरिद्वार और फिर बाद में मुजफ्फरनगर , मेरठ जिलों का दौरा कैसे कर आये। विश्वनाथ प्रताप सिंह की इन जनसभाओं में यद्यपि किसान यूनियन के महेन्द्र सिंह टिकैत स्वयं शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनके समर्थकों ने इन सभाओं के आयोजन

में काफी मदद की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा टिकैत के मध्य बढ़ती इस निकटता से भी अजीत सिंह चिन्तित हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा यह बयान दिये जाने पर कि अभी राजीव गांधी से इस्तीफा मांगने का समय नहीं आया है, लोकदल-अ के महासचिव सत्यप्रकाश मालवीय ने फौरन ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जो लोग यह मानते हैं कि राजीव गांधी से इस्तीफा मांगने का अभी समय नहीं आया है, वे गलत सोचते हैं। साथ ही उन्होंने तत्काल राजीव गांधी के इस्तीफे की मांग भी पेश कर दी। राजधानी के राजनीतिक हलकों में इसे लोकदल-अ द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया गया एक कैसा खुला संदेश माना जा रहा है, जिसका साफ मतलब है कि या तो हमसे बात करो, हमें महत्व दो, साथ लेकर चलो अन्यथा हम तुम्हारा विरोध करेंगे।

सत्यप्रकाश मालवीय ने 'माया' को बताया कि अभी तक न तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी कोई स्थिति स्पष्ट की है और न ही वह खुलकर मैदान में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? मालवीयजी जोर देकर कहते हैं, "अपनी आंखों से विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुजफ्फरनगर जाते हुए काफिले को देखा था, जिनमें तमाम कारों पर कांग्रेस के झंडे फहरा रहे थे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह अभी भी अपने आपको कांग्रेस से अलग नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए कैसे संभव होगा कि हम कांग्रेस के झंडे के साथ चल सकें।" लेकिन अजीत सिंह अभी इस विषय में कोई दो-टूक जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। क्या आप विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन करेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में मुस्कुराते हुए अजीत सिंह का जवाब था, "हां भी और न भी।" इसके बाद वह स्पष्ट करते हैं कि अभी तो कोई ठोस बात ही नहीं हो पायी है। जब तक स्थितियां और स्पष्ट न हों मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक निकटतम संबंधी तथा कांग्रेसी सांसद के माध्यम से अजीत सिंह तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मध्य 'समझ' विकसित करने का काम जारी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के यह संबंधी अजीत सिंह के सहपाठी हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त आरिफ मोहम्मद खां तथा अजीत सिंह के मध्य संबंध बना हुआ है।

भाजपा और वामपंथी : विपक्षी राजनीति के दो ध्रुवों—कम्युनिस्टों तथा भाजपाइयों—दोनों के ही बहुत निकट न जाने की विश्वनाथ प्रताप सिंह की कोशिश के बावजूद दोनों ही पक्षों से विश्वनाथ प्रताप सिंह का संवाद बना हुआ है। निश्चय ही कम्युनिस्ट दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से यह संवाद ज्यादा सार्थक शक्ल ले रहा है। कांग्रेस छोड़ने से पूर्व और उसके बाद भी जिन नेताओं से विश्वनाथ प्रताप सिंह की लंबी बातचीत हुई है, उनमें भारतीय जनता पाटर्ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी प्रमुख हैं। लालकृष्ण आडवाणी से उन्होंने दो हफ्ते के अन्दर तीन बार बातचीत की। अपनी तीसरी मुलाकात में विश्वनाथ प्रताप सिंह आडवाणी के इस सुझाव को मान गये कि अब वह अपने आपको कांग्रेसी नहीं कहेंगे तथा इस स्थिति को चुनौती नहीं देंगे कि उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया है। आडवाणी का कहना था कि इसके बाद ही उनके तथा विपक्षी दलों के मन में कोई ऐसी स्थिति बनती है, जब एक साथ मिलकर संघर्ष किया जा सके। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने मामले में तो यह बात स्पष्ट कर आये, पर अपने साथियों के संबंध में कुछ कहने में असफल रहे, जिन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और जो अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए अपने आपको सच्चा कांग्रेसी बताते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ के नेता विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू तथा आरिफ मोहम्मद खां का कहना है कि उनका निष्कासन गलत है।

आडवाणी से इन मुलाकातों के अतिरिक्त भाजपा के साथ बेहतर संबंधों का एक प्रमुख कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह के वे मित्र और शक्तियां भी हैं, जिन्होंने राजीव गांधी के ख़िलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह की खुलकर मदद की है। इनमें एक्सप्रेस समूह के मालिक रामनाथ गोयनका की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बतायी जाती है। यही कारण है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन देने के लिए सबसे ठोस प्रस्ताव लेकर अधिकारिक रूप से सबसे पहले आगे आने वाला दल भारतीय जनता पार्टी है।

आसानी से स्वीकार्य नहीं : बहुगुणा

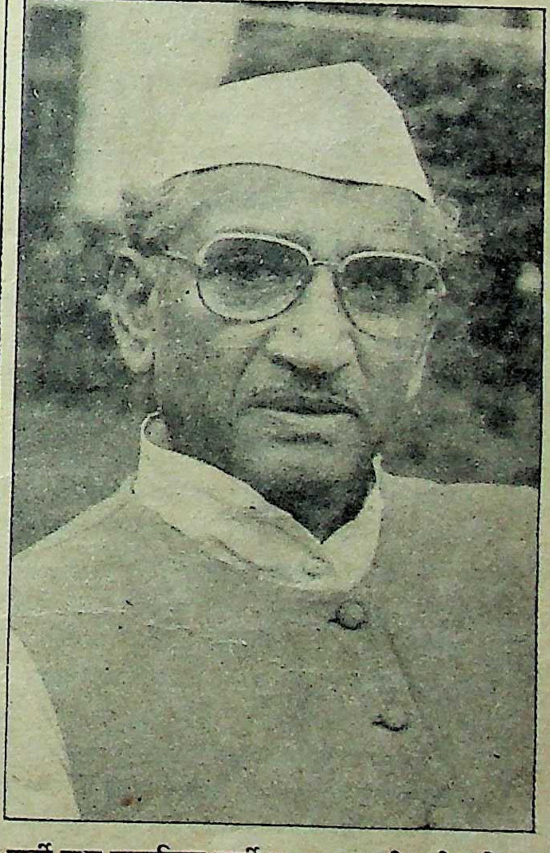

बोफोर्स के मामले में सी०आई०ए० का हाथ होने की बहस में काफी समय से एक सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण बनाये रखने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मध्य निश्चय ही पहले संबंध बहुत सुमधुर नहीं थे। राष्ट्रपति चुनाव में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनायी गयी भूमिका के बाद न केवल विपक्ष, अपितु विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी कम्युनिस्टों के प्रति एक संदेहपूर्ण दृष्टिकोण रखना स्वाभाविक था। किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे और निष्कासन के सात दिन बाद ही अचानक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राजीव सरकार के प्रति अपनाये गये आक्रामक रुख से स्थितियां बदली हैं। यद्यपि अभी तक मार्क्सवादी दलों ने इस संदर्भ में कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं की हैं, फिर भी नंबूदिरीपाद और वी०पी० सिंह के स्वरों में समानता से कुछ संकेत मिलते हैं। नंबूदिरीपाद कहते हैं, "यदि भगवान भी धरती पर उतर आयें, तो भी राजीव सरकार को नहीं बचा सकता।" इसके साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मध्यावधि चुनाव की मांग किये जाने और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा यही मांग दोहराने को दोनों ही पक्षों द्वारा एक सार्थक संकेत के रूप में लिया जा रहा है। इस संदर्भ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी का 'माया' से कहना था, "इस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के विषय में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी तक तो विश्वनाथ प्रताप सिंह न अपनी ठोस आर्थिक नीतियों के और न ही अपने भावी संगठन या दल—यदि वह कुछ बनाते हैं तो—के चरित्र को स्पष्ट कर पाये हैं।

हैदराबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा एन०टी० रामाराव, विजय राजे सिंधिया, बीजू पटनायक तथा देवीलाल के मध्य हुई भोज राजनीति में कुछ सार्थक रणनीति निकल कर आयेगी, ऐसी उम्मीद अधिकांश लोगों को नहीं थी। इसके बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह की दक्षिण भारत यात्रा पर सभी विपक्षी नेताओं की निगाह लगी हुई है। किंतु हेगड़े तथा रामाराव द्वारा निश्चय ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को उस गरमजोशी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला जो वह पहले ही खुद दिल्ली जाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को दे गये थे। रामाराव द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह को किस सीमा तक समर्थन दिया जायेगा, इस पर उन लोगों को फिलहाल संदेह है, जिन्हें रामाराव के मार्क्सवादियों से संबंध तथा भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की अंदरूनी कहानियों का पता है। दक्षिण में ही अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषगम तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मध्य कोई संबंध न बन पाने तथा करुणानिधि द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच बनी दूरी से भी राजनीतिक समीक्षकों का चौंकना स्वाभाविक है।

भावी रणनीति : इस बीच राजधानी में विपक्षी नेताओं के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह की भावी रणनीति के संबंध में दो राय प्रकट की ज़ा रही हैं। एक मत यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह धीरे-धीरे एक लोक संघर्ष समिति के नाम से किसी संयुक्त मोर्चे का गठन करेंगे, जिसमें विभिन्न विपक्षी दल, छोटे-छोटे संगठन तथा क्षेत्रीय शक्तियां शामिल होंगी। लोक संघर्ष समिति के गठन के साथ ही विश्वनाथ प्रताप सिंह व्यापक राष्ट्रीय संघर्ष व आंदोलन छेड़ेंगे। यदि ऐसी कोई कोशिश सफल होती है, तो यह कहना मुश्किल है कि कम्युनिस्ट दल उनका किस हद तक साथ देंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसमें देवीलाल, बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, जार्ज फर्नांडीस, शरद जोशी, सुरेन्द्र मोहन आदि तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी, छात्र संगठन तथा जे०पी० आंदोलन से जुड़े रहे पुराने सर्वोदयी कार्यकर्ता आदि उनके साथ आयेंगे। इस संदर्भ में जार्ज फर्नांडीस का 'माया' से कहना था, "जिस तरह आपातकाल में एकमात्र मुद्दा फासिज्म का विरोध था और उसके लिए सारे वैचारिक मतभेद भूलकर मार्क्सवादियों से लेकर जनसंघी तक मिलकर एक साथ लड़े थे, उसी तरह आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में फैला भ्रष्टाचार है। वह भी तब

जब देश का प्रधानमंत्री ही भ्रष्ट हो। अतः विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा सभी विपक्षी दल मिलकर यदि कोई संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनायें, तो मैं उसमें पूरी ताकत के साथ शामिल होऊंगा।" किंतु युवा जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीन्द्र भदौरिया का कहना था, "यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह सारे विपक्ष के साथ मिलकर कोई आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जहां एक तरफ आवश्यक है कि वह आर्थिक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी तथा शिक्षा नीति जैसे मुद्दों को उठाते हुए छात्र तथा युवा शक्ति को साथ लें, जिसके बिना कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना असंभव है।" लेकिन क्या इस आंदोलन या विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा विपक्ष की दोस्ती के बीच नेतृत्व का मुद्दा आड़े नहीं आयेगा, जिसके कारण पहले से विपक्ष विभाजित है? इस पर सुधीन्द्र भदौरिया का स्पष्ट जवाब था, "विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ही यह कह चुके हैं कि उन्हें भविष्य में कोई भी पद या गद्दी नहीं चाहिए। वह स्वयं ही सत्ता में भागीदारी की किसी भी संभावना को खुद बार-बार नकार चुके हैं। ऐसी स्थिति में नेतृत्व जैसे मुद्दे पर विश्वनाथ प्रताप सिंह का किसी विपक्षी नेता से झगड़ा हो, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। बशर्ते विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने वचन पर कायम रहें जो मुझे आशा है, वह रहेंगे।"

लेकिन विपक्ष तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मध्य संबंधों में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथी तथा उनका कांग्रेसी जनाधार। एक तरफ अरुण नेहरू तथा आपातकाल की प्रेस सेंसरशिप की याद दिलाने वाले विद्याचरण शुक्ल विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हैं, जोकि विपक्षी नेताओं के लिए बहुत हद तक अस्पृश्य हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्दर मौजूद वे असंतुष्ट कांग्रेसी विपक्ष के लिए अपाच्य हैं, जिन्हें खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस से निकलने के लिए मना किया हुआ है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि विपक्ष के बार-बार लोक संघर्ष समिति बनाने या संयुक्त मोर्चा गठित करने के सुझाव को विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वीकारने में इसलिए आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि वह अभी भी न केवल अपने कांग्रेसी जनाधार पर आश्रित हैं, बल्कि उनकी रणनीति सिर्फ इतनी है कि विपक्ष के साथ सीमित संबंध बनाये हुए वह राजीव सरकार पर इतना दबाव डालें कि वह चरमरा उठे और कांग्रेसी सांसद घबड़ाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वापस ले आयें। इस आशा के साथ कि अब उन्हीं की लोकप्रियता उन्हें दुबारा संसद तक पहुंचा सकती है। यदि कहीं ऐसा हो गया, तो शायद यह देश के राजनीतिक जीवन की सर्वाधिक विचित्र घटना होगी। जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह को चुनौती देने वाला शायद ही कोई हो, क्योंकि आज विश्वनाथ प्रताप सिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा करने वाला विपक्ष कल किस मुंह से कांग्रेस के शीर्ष नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह का विरोध कर पायेगा। यह आशंका कितनी भी क्षीण हो, पर विपक्ष के लिए एक दुःस्वप्न के समान है।

छाया: सुनील सक्सेना, गिरीश श्रीवास्तव,
मनमोहन शर्मा, राजीव चावला

साक्षात्कार/चंद्रशेखर

पहले वी०पी० सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें

माया: विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई में आप का दल किस सीमा तक उनका समर्थन करेगा? क्या आपने इस संदर्भ में अपनी कोई रणनीति तय की है?

चंद्रशेखर: पहले तो अभी खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह तय करना है कि क्या उन्हें हमारे समर्थन-सहयोग की आवश्यकता है भी या नहीं। फिर अभी तक उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यदि वह कोई व्यापक जनांदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके आधारभूत राजनीतिक मुद्दे, वृहत्तर नीतियां व दिशा क्या होंगी? कांग्रेस से अलग होने के बाद से उनके द्वारा की गयी रैलियों व वक्तव्यों से मोटे तौर पर जो बात निकल कर आयी, वह यह है कि वह कांग्रेस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई में हम उनका समर्थन करते हैं। भ्रष्टाचार के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम पूरा-पूरा सहयोग देंगे। अब तक उनके जो वक्तव्य आये हैं, उनके अनुसार वह न तो कोई राजनीतिक दल बनायेंगे और न ही किसी दल के साथ जायेंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल के साथ वह किस तरह के और कैसे संबंध रखना चाहते हैं तथा हमसे किस प्रकार के और कितने सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जब तक पहले खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह इस विषय पर निर्णय लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते, तब तक हम कैसे अपने आप तय कर लेंगे?

माया: लेकिन अभी हाल में आप की विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुलाकात हुई थी। उस समय क्या आप दोनों के मध्य इन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई?

चन्द्रशेखर: मैंने तो किसी समाचारपत्र में यह बयान नहीं दिया है कि मेरी विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुलाकात हुई या मैंने उन्हें यह राय दी अथवा उन्होंने यह बात कही।

माया: यह सही है कि आपने अपनी मुलाक़ात की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। पर यह तो सच है कि गत २४ जुलाई को आप दोनों के मध्य भेंडसी (भारत यात्रा केन्द्र) में दो घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई।

चन्द्रशेखर: मैं नहीं मानता क़ि मेरी हर मुलाकात राष्ट्रीय राजनीति में कोई सार्वजनिक घोषणा की ख़बर होती है। न ही मैं अपने आप को इसके लिए उत्तरदायी मानता हूं कि मैं अपनी सब मुलाकातों का ब्यौरा समाचार पत्रों को देता फिरूं, जैसे कुछ अन्य लोगों ने किया है। हो सकता है कि उन बड़े नेताओं की मुलाकातों का इतना राष्ट्रीय महत्व हो कि हर मुलाकात के बाद अखबार वालों को बुलाकर उसका ब्यौरा दिया जाये। मैं इस तरह की मुलाकातों को प्रचारित कर लोगों को न तो कोई झूठा दिलासा देना चाहता हूं और न ही इस तरह समाचारपत्रों में प्रसिद्धि पाने की मेरी कोई लालसा है। मैं तो एक साधारण नागरिक हूं और विश्वनाथ प्रताप सिंह से मेरी मुलाकात व्यक्तिगत थी। मैंने दो घंटे में उनसे पता नहीं क्या-क्या बातें कीं? विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैं कोई आज से नहीं, उन दिनों से जानता हूं, जब वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। स्वाभाविक है मेरी जो राय है, वह सलाह के रूप में मैंने उन्हें दी होगी पर वह सार्वजनिक घोषणा की चीज नहीं है।

माया: आपसे पहले अनेक विपक्षी नेताओं—लालकृष्ण आडवाणी, देवीलाल, रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक आदि ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से वार्ताएं की थीं, जिनमें एक लोक संघर्ष

समिति या संयुक्त संघर्ष मोर्चा के गठन की संभावना पर बातें हुई थीं। ऐसी किसी अवधारणा के संदर्भ में आपका क्या मत है? क्या आप उसमें शामिल होंगे?

चन्द्रशेखर: यदि किसी व्यापक व दीर्घकालिक संघर्ष के लिए मोर्चे की कोई योजना है, तो वह तो तभी संभव हो पायेगा, जब बुनियादी राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक मुद्दे स्पष्ट हों, जिसके बिना व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इस संदर्भ में तो कोई ठोस प्रस्ताव मेरी जानकारी में नहीं है। अभी तक तो सिर्फ यही बात सामने आयी है कि कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष किया जाये। इस संघर्ष को मजबूत करने में हम पूरी ताकत से साथ देंगे। हेगड़े जब विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलने जा रहे थे, उससे पहले भी उनसे मेरी बात हुई थी और जब वह बात करके लौटे, तब भी सारे वार्तालाप को उन्होंने दल की राजनीतिक मामलों की समिति के सामने रखा था। मैंने खुद हेगड़े से कहा था कि आप जिस सीमा तक उनके साथ इस लड़ाई में जाना चाहें, जायें।

माया: क्या यह बात आप पर भी लागू है?

चन्द्रशेखर: मैं किसी को भी ऐसी कोई राय नहीं देता हूं, जिसे मैं अपने लिए गलत मानता हूं या जिस पर मैं खुद अमल न करूं। सिर्फ हेगड़े की ही बात नहीं है, पूरी जनता पार्टी और मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वालों का पूरी तरह साथ दूंगा। क्योंकि हम खुद इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते आ रहे हैं।

माया: कहा जाता है कि कुछ विपक्षी नेताओं में विश्वनाथ प्रताप सिंह को लेकर इसलिए भी झिझक है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में हो?

चन्द्रशेखर: आपके मित्र लोग (पत्रकार) स्वतंत्र हैं, जैसा सोचें वे लिखें। पर पहले यह तो बताइए कि क्या आज पूरे देश में कोई जन-आन्दोलन खड़ा हो गया है, जिसके नेतृत्व के लिए संघर्ष हो। यदि आपको पता हो हमें भी बताइये। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा की गयी सभाओं की ही बात कर रहे हैं, तो वह 'आन्दोलन' केवल इतना है कि कांग्रेस में घूस ली गयी। इतना ही है, तो इस बात की सबसे ज्यादा प्रामाणिक जानकारी जिसके पास होगी, जिसने इसे निकटता से देखा होगा, वही तो यह बात सबसे आगे बढ़ कर कह पायेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में थे। उन्होंने इसे सबसे निकट से देखा। मैं तो नहीं था वहां। अतः वही इस बात को देश के सामने सबसे बेहतर ढंग से रख पायेंगे। हम इसमें सहयोग देंगे। मैं इसे कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता, पर राजनीति में कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। उस मर्यादा का उल्लंघन करके कोई बदलाव आ जाये, वह न तो टिकाऊ होगा, न जनहित में। अतः हम उन्हें जो सहयोग देंगे, वह राजनीतिक सिद्धांतों की मर्यादा की सीमाओं को लांघकर नहीं और न हम जबरदस्ती उनके साथ जाने वाले हैं। हमारे द्वारा उन्हें सहयोग देने के पीछे सैद्धान्तिक कारण होंगे न कि तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ।

माया: क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले दिनों हरियाणा चुनाव तथा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को दो बार ऐसे मौके मिले, जब वह एकजुट हो अपनी एकता दिखा सके। पर वह दोनों बार विभाजित रहा। क्या इससे यह धारणा नहीं बनती कि भविष्य में भी मिलने वाले मौकों में भी विपक्षी नेता एकजुट नहीं हो पायेंगे?

चन्द्रशेखर: हरियाणा चुनाव में जनता पार्टी व लोकदल (अजीत सिंह) को छोड़ लगभग सभी विरोधी दल एकजुट थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हरियाणा में लोकदल को जनता पार्टी की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि जनता पार्टी को साथ लिये बिना भी वे सत्ता में आ जायेंगे और ऐसा हुआ भी। राष्ट्रपति चुनाव में मोटे तौर पर सभी विपक्षी दल, भाजपा को छोड़ कर, एक साथ थे। उसमें विपक्ष के प्रत्याशी घोषित करने से पहले एक दो दिन कम्युनिस्टों ने जो भूमिका निभायी, उसे मैं उचित नहीं मानता। प्रारम्भ में भारतीय जनता पार्टी को नहीं लिया गया वह भी गलत था। बाद में भाजपा ने खुद आने से इनकार कर दिया तथा चुनाव बहिष्कार किया। यह उनकी भूल थी। इस संदर्भ में मैं कृष्णा अय्यर की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने शुरू से साफ कहा कि मैं सारे विरोधी दलों की सहमति से चुनाव लड़ूंगा, भाजपा की सहमति भी ली जाये।

राजनीति में कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। उस मर्यादा का उल्लंघन करके कोई बदलाव आ जाये, वह न तो टिकाऊ होगा, न जनहित में। अतः हम उन्हें जो सहयोग देंगे, वह राजनीतिक सिद्धांतों की मर्यादा की सीमाओं को लांघकर नहीं और न हम जबरदस्ती उनके साथ जाने वाले हैं।

माया: फिर इसमें गड़बड़ी कैसे हो गयी?

चन्द्रशेखर: मैं नहीं जानता। एन०टी० रामारावजी पर भाजपा से बात करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बताया कि उनकी भाजपा से बात हुई है। बाद में रामारावजी ने मेरे सामने आडवाणी साहब से फोन पर बात की। मैं नहीं जानता उधर से फोन पर आडवाणी जी ने क्या कहा, पर रामारावजी ने मुझे बताया कि भाजपा कृष्णा अय्यर को समर्थन देने को तैयार है। पर तीन दिन बाद उन्होंने बहिष्कार की घोषणा कर दी। मैं नहीं जानता रामारावजी को ऐसा भ्रम कैसे हो गया। बाद में आडवाणीजी से मुलाकात होने पर मैंने उनसे इस निर्णय के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने यह निर्णय बहुत सोच-विचार कर लिया था तथा इसके बहुत और कारण भी हैं।

माया: क्या जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं?

चन्द्रशेखर: जितनी हमारी ताकत है, प्रारंभ से आज तक हमने पूरा प्रयास किया है।

माया: आप पर दबे-छुपे यदा-कदा आरोप लगता रहा है कि आपने विपक्षी दलों की एकता में जो सार्थक भूमिका हो सकती थी, वह नहीं निभायी। उलटे कई बार आपके चलते यह प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है?

चन्द्रशेखर: यह आरोप दबे-छुपे नहीं, सीधे-सीधे और खुलेआम लगे हैं और कई बार लगते रहे हैं। इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं अन्य नेताओं से बहुत कम संपर्क करता हूं। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोगों से मेरा निकट का संपर्क रहा है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अतः मैं उनसे मिल कर अनावश्यक रूप से उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता हूं और न ही मैं लोगों को झूठी आशा बंधाने का काम करता हूं।

माया: जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी विपक्षी दलों, संघर्षशील समूहों व व्यक्तियों के एक व्यापक मोर्चे को बना कर एक जन-आन्दोलन खड़ा करने की योजना बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है। इस दिशा में आपने क्या किया?

चन्द्रशेखर: मैंने अन्य विपक्षी दलों से इसके लिए बात की है, सभी को पत्र डाला है। कुछ के जवाब आये हैं, शेष अभी अपने यहां विचार कर जवाब देंगे। उसके बाद ही इस दिशा में प्रगति होगी।

—पुनीत टण्डन

मुजफ्फरनगर में राजा मांडा

अभियान और तेज हुआ

मुजफ्फरनगर की उस ऐतिहासिक सभा की रिपोर्ट, जिसमें राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार राजीव गांधी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ने की घोषणा की :

तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेइमानों का राज बदल दो', 'राजीव गांधी देख लो, जनता किसके साथ है', जैसे नारे पहली बार उस मंच से लगाये गये, जिस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह मौजूद थे। इसके पूर्व तक किसी भी जन सभा में राजा मांडा ने इस तरह के नारे लगाने की लोगों को अनुमति नहीं दी थी।

इंका से 'निष्कासन' के बाद राजा की पहली जनसभा २६ जुलाई को मुजफ्फरनगर में थीं। दिल्ली दरबार की निगाहें इस सभा पर टिकी हुई थी। मुजफ्फर नगर का जिला प्रशासन बड़े पसोपेश में था—सभा की अनुमति दी जाये या न दी जाये। एक दिन पूर्व ही वीर बहादुर सिंह यह कह चुके थे, "राजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह जहां चाहें आ-जा सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी के किसी सदस्य ने उनका साथ दिया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसी कार्रवाई के तहत २५ जुलाई को ही मुजफ्फरनगर की जिला कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गयी थी। इसी कमेटी ने राजा की सभा का आयोजन किया था।

पार्टी से हटने के बाद राजा की यह सभा एक तरह से ऐतिहासिक ही थी। राजा के साथ अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां, रामधन, सत्यपाल मलिक सहित इंका के आधा दर्जन सांसद इस सभा को संबोधित करने मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। सभा में पहली बार न केवल विद्रोहियों के तेवर देखने को मिलें, वरन इसी सभा में 'राजीव गांधी हटाओ' अभियान की भी घोषणा कर दी गयी।

सारी आशंकाओं और अफवाहों को निर्मूल सिद्ध करती हुई राजा मांडा की इस जनसभा में बेहिसाब भीड़ थी। सभा का आयोजन राजकीय इंटर कालेज के मैदान में किया गया था। तमाम दर्शक जगह न मिलने के कारण पेड़ों पर चढ़े हुए थे। आसपास के मकानों की छत पर जिस तरह लोग कब्जा किये हुए थे, उसे निश्चित रूप से ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कहा गया। प्रात:काल से ही किसान मजदूर नारे लगाते हुए सभास्थल पर पहुंचने शुरू हो गये थे। कई के हाथों में इंका के झंडे थे। इंका के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष जगवीर सिंह, दो हजार से अधिक की भीड़ लेकर सभा में आये थे। कई महीनों के बाद उस दिन आकाश में बादल छाये हुए थे। इस वजह से तपती गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की।

सभा स्थल पर पुलिस दूर-दूर तक दिखायी नहीं दी। स्वयंसेवक ही व्यवस्था बना रहे थे। राजा और उनका काफिला करीब एक बजे सभा स्थल पर पहुंचा। उस समय भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। काफी देर तक 'राजा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं', 'राजा खुलकर बोलो, बेईमानों का भांडा फोड़ो', 'राजीव-बच्चन मुर्दाबाद' के गगनभेदी नारे काफी देर तक गूंजते रहे।

राजा की गर्जना : उस दिन पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी और उनकी सरकार के खिलाफ जेहाद का ऐलान किया। राजा मांडा ने अपने भाषण की शुरुआत सूखे की समस्या से तथा समापन वीर बहादुर के भ्रष्टाचार से किया। वह बोले, "इस शताब्दी के भयंकरतम् सूखे से झुलसते किसानों की किसी भी मंत्री ने खैर-खबर लेनी तो दूर, एक शब्द भी नहीं कहा। सब मंत्री दिल्ली में बैठे पार्टी से कुछ लोगों के निष्कासन की खुशी में पार्टियां देकर जश्न मनाते रहे। उन्हें क्या मालूम कि जब गन्ने की पत्तियां सूखकर पीली पड़ जाती हैं, तब किसान का दिल भी ऐंठ जाता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली कहीं और है और यह देश कहीं और।"

वी०पी० सिंह का कहना था जनता की शक्ति सर्वोच्च है। सत्ता की इमारत गिर सकती है, लेकिन धरती पर खड़े लोग नहीं गिर सकते। सरकार में बैठे लोग बड़ी तरकीब से किसानों की जेब से पैसा निकलवा लेते हैं।

मुजफ्फरनगर के किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन जैसा आंदोलन छेड़े जाने की मांग

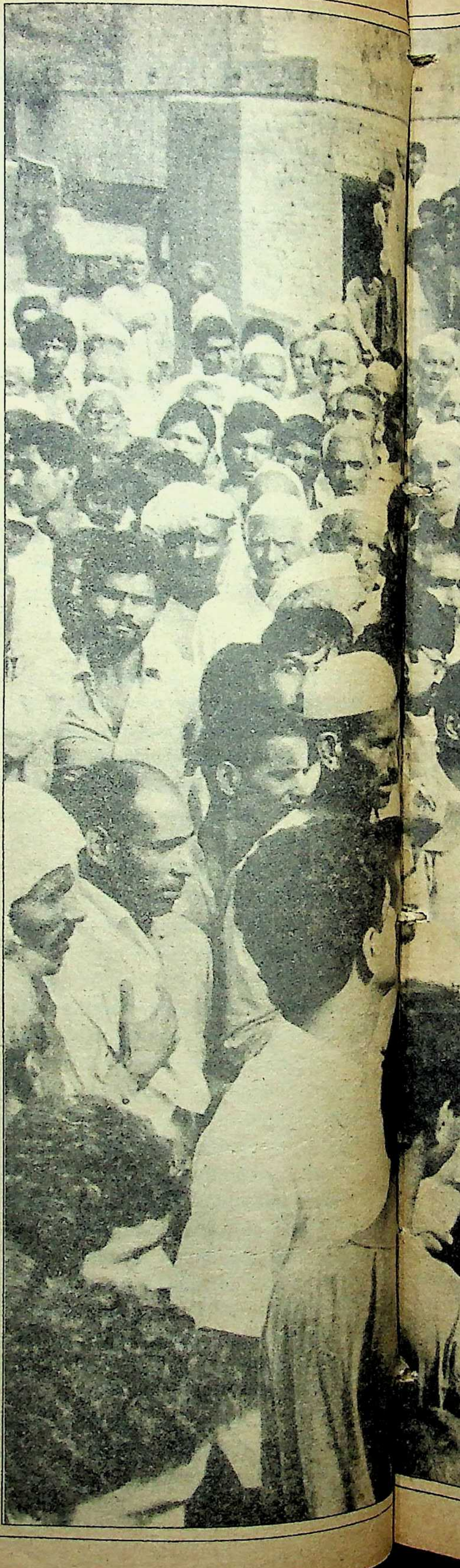

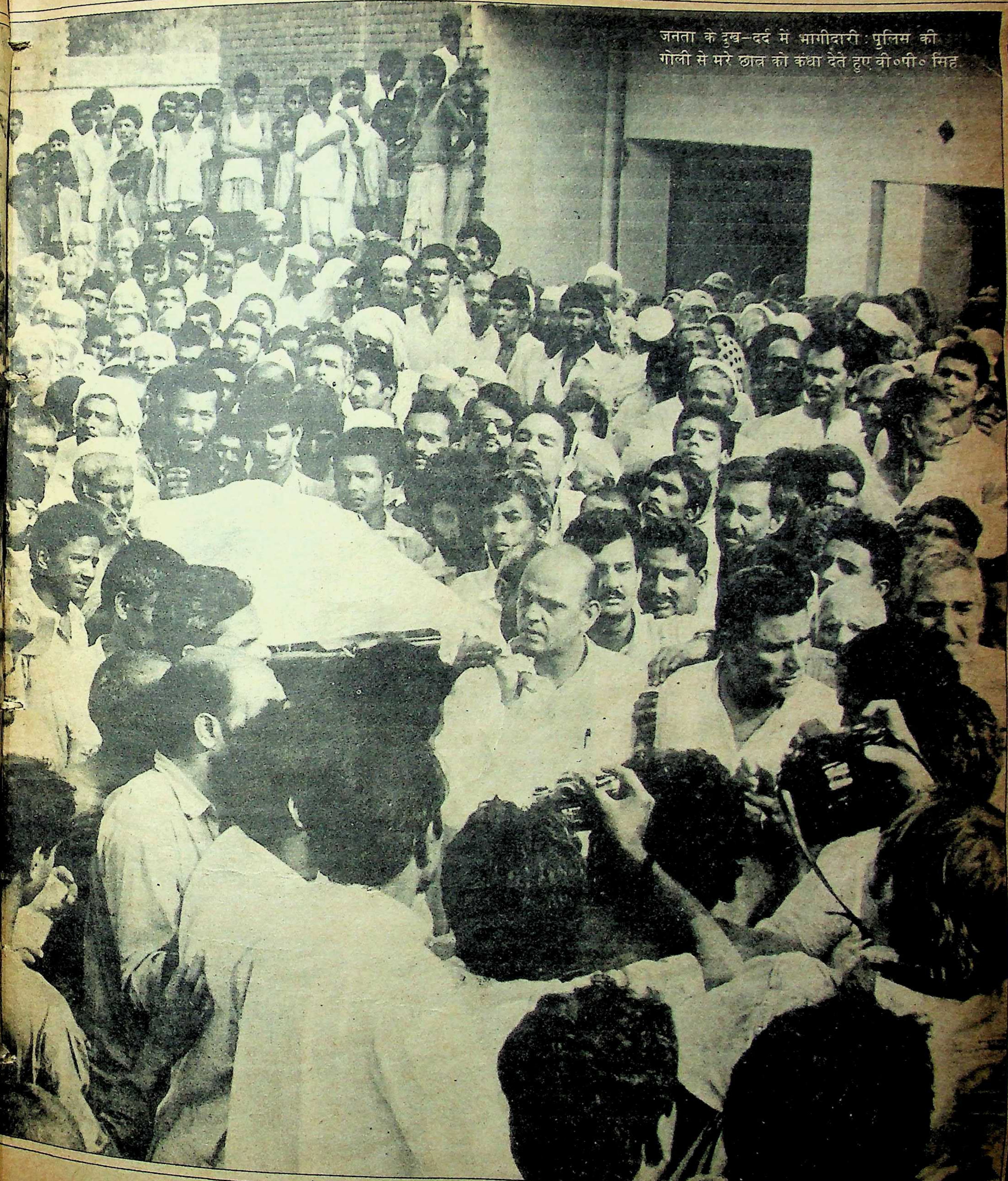

जनता के दुख-दर्द में भागीदारी : पुलिस की गोली से मरे छात्र को कंधा देते हुए वी०पी० सिंह

लों को रेशमी, घने व मुलायम बनानेवाला केश तेल
आयुर्वेद सेवाश्रम का ब्राह्मी व आँवला का मेल

सेवाश्रम
ब्राह्मी आँवला केश तेल
BRAHMI AMLA HAIR OIL
bajaj PRODUCT
AYURVED SEVASHRAM LTD

मेरे काले घने और
लम्बे बालों का रहस्य है
आयुर्वेद सेवाश्रम का
ब्राह्मी आँवला केश तेल
इसमें आँवला ही नहीं ब्राह्मी भी है
बजाज का बेहतरीन
उत्पादन

Poonam Dhillon

सेवाश्रम

ब्राह्मी आँवला
केश तेल

आयुर्वेद सेवाश्रम लि.
उदयपुर . वाराणसी . हैदराबाद

bajaj group

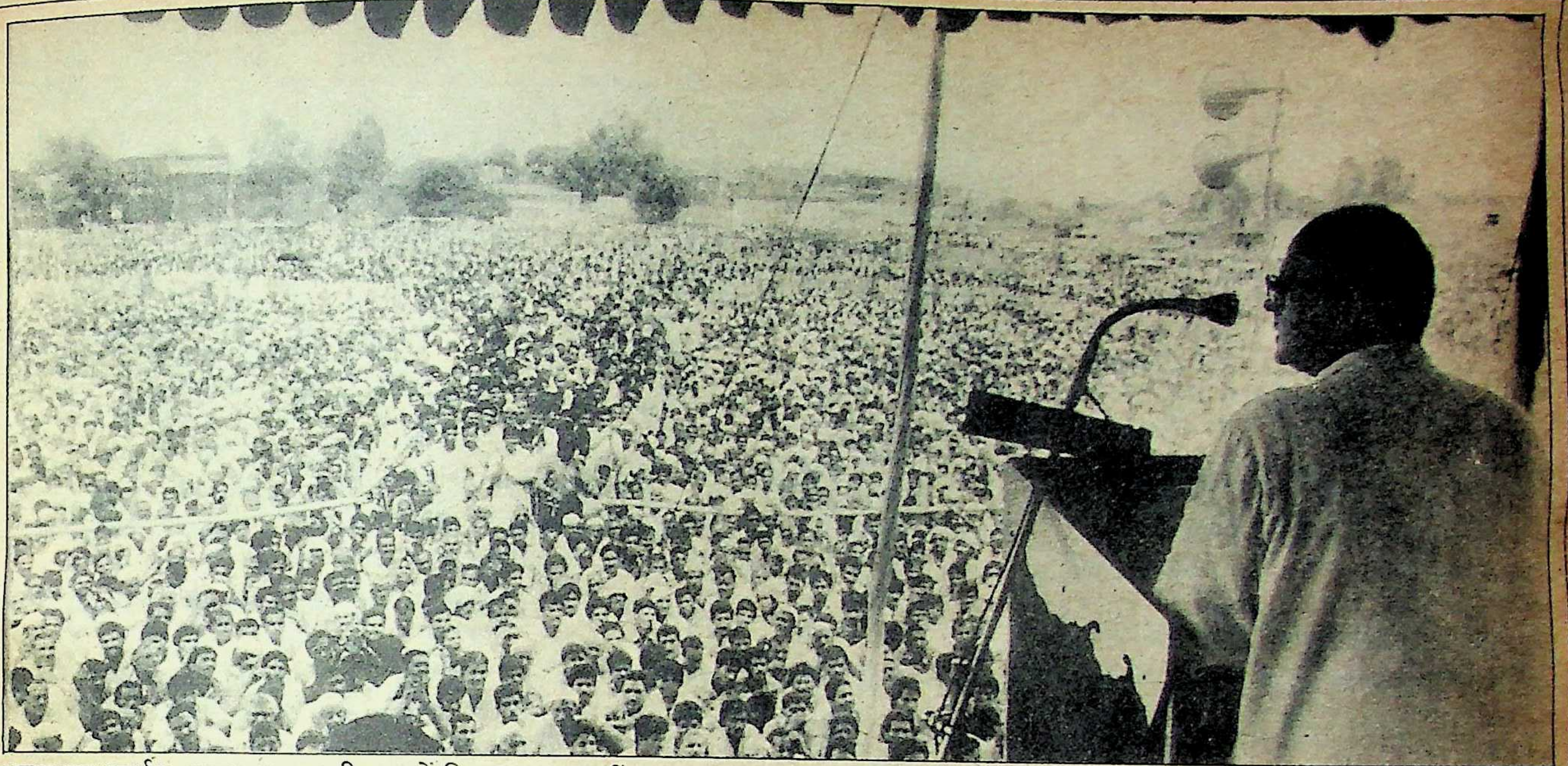

अपार जन समर्थन : मुजफ्फरनगर की सभा में विश्वनाथ प्रताप सिंह

पर राजा बोले, "उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखे के बावजूद तमाम सरकारी ट्यूबवैल खराब पड़े हैं। युवकों को देखना चाहिए कि कहां-कहां ट्यूबवैल खराब हैं। यदि एक सप्ताह के अन्दर खराब पड़े ट्यूबवैल चालू नहीं होते, तो इस किसान विरोधी सरकार को न चलने दो। इस संघर्ष में हम पूरी तरह किसानों के साथ हैं।"

इस सभा में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर प्रहार करते हुए बोफोर्स, स्विस बैंक के खातों और बच्चन-बंधुओं की सम्पत्ति के बारे में खुलकर चर्चा की। उनका कहना था, "जिस दिन प्रधानमंत्री ने अजिताभ के खिलाफ जांच बैठायी उसी दिन मेरी जीत हो गयी थी। मुजफ्फरनगर से ही मैंने अपना सिर काटकर प्रधानमंत्री को पेश करते हुए कहा था, "चाहे तो मुझे कांग्रेस से निकाल दो, लेकिन मुझे नहीं निकाला गया। जब मैंने अजिताभ बच्चन की सम्पत्ति की जांच की मांग के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो वही खत मेरी खता बन गया। मुझ पर, अरुण नेहरू पर और आरिफ पर हमले किये गये हैं। ये गुण्डे हमें तो मार सकते हैं, लेकिन ७५ करोड़ लोगों में कितनों की हत्या करेंगे?"

विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उस दिन अरुण, आरिफ के अतिरिक्त सांसदों में सत्यपाल मलिक, रामधन, राजकुमार राय, मानवेन्द्र सिंह मुजफ्फर नगर के इंका विधायक व पूर्वसहकारिता राज्यमंत्री दीपक कुमार और महाराष्ट्र के मजदूर नेता शरद जोशी, मुजफ्फरनगर इंका-अध्यक्ष सोमाश प्रकाश सहित दर्जनों नामी-गिरामी नेता थे। कुछ लोगों ने तो 'विश्वनाथ प्रताप सिंह फैंस एसोशिएशन' भी गठित कर ली है।

सरकार बदलने का आह्वान : अधिकांश वक्ताओं का कहना था कि यह लड़ाई वी०पी० सिंह की नहीं, कौरवों और पांडवों का युद्ध है। सांसद सत्यपाल मलिक का मत था कि वी०पी० सिंह के विरुद्ध साजिश उसी समय शुरू हो गयी थी, जब उन्होंने किर्लोस्कर और थापर को हथकड़ी लगवाकर जेल भेजा था। इसी के बाद उस व्यक्ति का नम्बर था जो देश का सबसे बड़ा चोर था। लेकिन उसकी पहुंच राजीव गांधी के घर तक थी, इसीलिए वी०पी० सिंह की छुट्टी कर दी गयी। ढाई वर्ष में राजीव गांधी किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोले, बोले भी तो अनाज का मूल्य कम करने की अपील की। भारत के मजदूरों को उन्होंने दुनिया का सबसे कामचोर मजदूर बता डाला। रिश्वतखोरी पहले भी होती थी, किन्तु जब देश का सबसे बड़ा आदमी (राजीव गांधी) ही यह कह दे कि दलालों को हटाकर मुझे और मेरे घरवालों को कमीशन दो, तो इससे बुरा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। यदि लोग कम-से-कम ढाई और अधिक-से-अधिक सात वर्ष का कष्ट उठा लें, तो देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए सरकार को बदला जा सकता है।

अरुण नेहरू का कहना था, "१९८४ के चुनाव में एक नारा लगा था कि 'इंदिराजी की अंतिम इच्छा बूंद-बूंद से देश की रक्षा,' यही देश की भावना थी। हम किसी एक व्यक्ति के कारण चुनाव नहीं जीते थे। यह वह कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए इंदिराजी ने बलिदान दिया था। हमें इंदिरा की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। आज केन्द्र सरकार आम आदमी की शक्ति से घबरा गयी है। प्रधानमंत्री निवास पर किराये की भीड़ जमा कराकर हम लोगों के यहां हमले कराये जा रहे हैं। इन सबसे मैं नहीं डरता।"

आरिफ मोहम्मद खां का आरोप था, "सरकार ने देश की एकता और अखण्डता के दुश्मनों से समझौता कर डाला। हमने चुनाव के दौरान किये गये वादों की याद दिलायी, तो हमें पार्टी से निकाल दिया गया। हम दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के हंसते चेहरे को देखते हैं, तो एक ही प्रश्न उठता है। किस पर हंस रहे हैं। रक्षा सौदे पर या सुरूर-पुर के बच्चों पर जिन्हें गोली से भून दिया गया। आप विमानों के अहपरण की खबरें पढ़ते होंगे कि कैसे पायलेट धमकी के आगे अपना रास्ता बदल देता है, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे।"

विधायक दीपक कुमार (जिनका हरिजन विधायकों पर अच्छा प्रभाव है) ने सभा-मंच से ही घोषणा की, "एक समाचार पत्र ने मेरे बारे में यह भ्रांति फैलाकर मुझे ब्लैकमेल एवं अपमानित करने का प्रयास किया है कि मैं वी०पी० सिंह के साथ नहीं हूं। राजाजी के चरणों में एक विधायक पद तो क्या मैं अपना सम्पूर्ण जीवन सर्मपित करता हूं। सांसद रामधन का कहना था कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

असर : राजा की इस सभा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जहां व्यापक प्रभाव पड़ा है, वहीं मुज़फ्फरनगर की पूरी कांग्रेस पार्टी राजा के साथ हो गयी है। इस सारे क्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि कुछ महीने पहले तक अरुण नेहरू का साथ देनेवाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावी इंका नेता विद्याभूषण ने अचानक अरुण नेहरू से नाता तोड़ लिया है। इस बारे में विद्याभूषण का कहना है, "मैं शुरू से ही इंदिरा परिवार के साथ था। आज भी उसी परिवार के साथ हूं। अरुण नेहरू ने चूंकि इंदिरा परिवार से नाता तोड़ा है। इसलिए मैंने भी उनसे अपने संबंध समाप्त कर लिये हैं।"

लेकिन इस बारे में इंका के ही लोग बताते हैं, "विद्याभूषण का टिकट राजा साहब ने ही काटा था, इसी कारण वह राजा का साथ नहीं दे रहे हैं।"

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंका की डगमगाती नैया को सम्हालने के लिए अब वीर बहादुर सिंह ने विद्याभूषण का सहारा लेना शुरू किया है। देखना है, वह इस कार्य में कितने सफल होते हैं।

—लखनऊ ब्यूरो

—छाया : मनमोहन शर्मा

भारत-श्रीलंका समझौता

खतरों से घिरा साहसी कदम

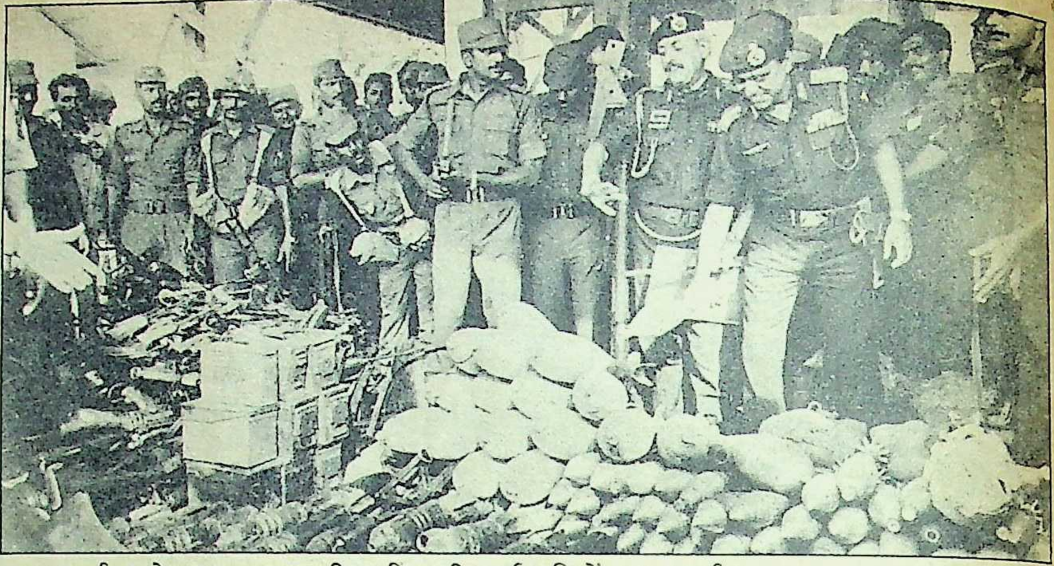

शस्त्र समर्पण : मेजर जनरल हरकीरत सिह की उपस्थिति में शस्त्र समर्पण

कुछ अरसा पहले जिस श्रीलंका सरकार को भारत की राहत सामग्री तक से परहेज था, उसी ने भारत सरकार से झटपट ऐसा 'शांति समझौता' कर लिया कि आज भारतीय सेना के सशस्त्र जवान श्रीलंका में शांति-स्थापना का कार्य कर रहे हैं और पाक और इस्रायली सलाहकारों को रुखसत कर दिया गया है। जो तमिल उग्रवादी पृथक तमिल राष्ट्र से कम, किसी शर्त पर राजी होने के लिए तैयार नहीं थे, आज वे अपने हथियार सौंप रहे हैं और जो श्रीलंका सरकार इन तमिलों को वहां से भगाने पर आमादा थी, उसी ने १३ प्रतिशत श्रीलंका की तमिल आबादी के लिए ३३ प्रतिशत इलाके को स्वायत्तशासी बनाना मंजूर कर लिया है। तमिल नेताओं को समझौते से दूर रखे जाने का मलाल है, तो श्रीलंका की सेना में अपनी ही सरकार द्वारा किये गये समझौते से इतना असंतोष है कि एक नौसैनिक ने तो 'गार्ड आफ आनर' के समय ही राजीव गांधी पर घातक हमला कर दिया था। शुरू में सफल दिखायी देनेवाले, लेकिन विरोधाभासों से घिरा यह समझौता सफल हो पायेगा या 'पंजाब समझौते' की तरह समझौता हो जाने के बावजूद वहां जातीय हिंसा जारी रहेगी ?

> **भा**रत-श्रीलंका समझौते में हम कोई पक्ष नहीं हैं। यद्यपि हम भारतीय सेना को अपने हथियार हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गये हैं, फिर भी हम पृथक तमिलराष्ट्र के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भारत सरकार ने हमें समझौते की जानकारी देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये। इस वक्त तक इस समझौते की प्रति सिर्फ आपके (पत्रकारों) पास है, हमारे पास नहीं।"
>
> —वी० प्रभाकरण एल०टी०टी०ई० चीफ
> ५ अगस्त, १९८७

श्रीलंका पिछले चार सालों से बर्बर जातीय नरसंहारों से रक्तरंजित है। इस दौरान वहां शांति स्थापित होने के ऐसे प्रबल आसार पहले कभी दिखायी नहीं दिये, जितने कि आज दिखायी दे रहे हैं। पश्चिमी समाचार माध्यमों ने तो श्रीलंका को दक्षिण एशिया का लेबनान कहना शुरू कर दिया था, लेकिन २९ जुलाई, १९८७ को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक सादे, लेकिन भव्य समारोह में छह पृष्ठीय भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने से इस क्षेत्र का सारा परिदृश्य ही बदल गया है। बहरहाल, समझौता होने के अंतिम क्षणों तक दोनों देशों में संदेह और निराशा का वातावरण था। राजीव गांधी की दो दिवसीय कोलंबो यात्रा के संबंध में पी०टी०आई० से बातचीत करते हुए एल०टी०टी०ई० लीडर वी० प्रभाकरण ने इस दौरे को 'विश्वासघाती दौरे' की संज्ञा देते हुए समझौते को तमिलों की पीठ में छुरा घोंपना बताया है। यहां तक कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और जगजाहिर भारत-विरोधी प्रेमदास ने भी हस्ताक्षर से पूर्व इस समझौते पर जनमत-संग्रह की मांग की थी। वह तो इस समझौते के विरोध में हैं ही, वहां के प्रमुख विपक्षी दल एस०एल०एफ०पी० की नेता श्रीमाओ भंडारनायके ने भी इस समझौते की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के लिए गंभीर खतरा बताया है।

समझौते का विरोध : स्वयं श्रीलंका में इस समझौते के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। अमपराई में १०० बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में पांच हजार सिंहलियों ने राजीव गांधी की यात्रा के विरोध में प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए विशेष कमाण्डो दल को बुलाना पड़ा। 'मदरलैण्ड प्रोटेक्शन फ्रंट' (मातृभूमि सुरक्षा मोर्चा) के झंडे तले बौद्ध भिक्षुओं ने एक विरोध सभा भी की।

समझौते के विरोध का तो आलम यह था कि जिस समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें श्रीलंका के २९ मंत्रियों में से ७ मंत्री शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री प्रेमदास ने भी इस 'समझौता-समारोह' का बहिष्कार किया था। सिंहली युवकों और बौद्ध भिक्षुओं की उपद्रवकारी भीड़ सड़कों पर निकल आयी थी और उसने समझौते के विरोध में जुलूस निकालने तथा बसों, ट्रेनों और भवनों को जलाने की कोशिशें कीं। एक भारतीय पत्रकार के अनुसार, "यह भारत और तमिल विरोधी भावनाओं का सैलाब है। सिंहलियों के लिए तमिल और भारत दोनों एक ही हैं। उन्हें लगता है कि मानो जे०आर० जयवर्द्धने ने सिंहलियों का अपमान किया है और देश को भारत के हाथों बेच दिया है।" उपद्रवों की संगीनता का पता इसी से चल जाता है कि कोलंबो जिले में सरकार को कर्फ्यू लगाकर 'देखते ही गोली मारने' के आदेश देने पड़े। इसमें १८ प्रदर्शनकारी मारे गये।

सिंहलियों और बौद्ध भिक्षुओं के प्रबल विरोध को देखते हुए समझौते की सफलता संदिग्ध हो जाती है। आखिर सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह थी, जिसने भारत और श्रीलंका को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने

के लिए मजबूर कर दिया था और इस समझौते की सफलता की क्या संभावनाएं हैं? इन दोनों सवालों के जवाब सरल नहीं हैं।

समझौते की मजबूरी : राष्ट्रपति जयवर्द्धने समझौते पर अचानक दस्तखत करने का कारण 'ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूलता' बताते हैं। उनका कहना है कि इसी कारण वह अपने हठ को छोड़कर समझौता करने पर मजबूर हुए। लेकिन बताया जाता है कि असली कारण आर्थिक है। श्रीलंका के वित्त मंत्री रोनेई डी मैल ने जयवर्द्धने को अहसास करा दिया था कि तमिलों की उग्रवादी कार्यवाहियां शुरू होने के बाद पिछले चार वर्षों में सुरक्षा व्यय (२० लाख रुपए प्रतिदिन) कई गुना बढ़ गया है। श्रीलंका चाय के कम उत्पादन के कारण वैसे ही आर्थिक संकट में है और ऐसी स्थिति में वह तमिलों के खिलाफ अनिश्चित समय तक लड़ाई जारी नहीं रख सकता।

इस समझौते को संभव बनाने में कई और कारण भी जिम्मेदार रहे हैं। जिस तरह अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने इस समझौते का समर्थन किया, उससे प्रतीत होता है कि यह समझौता व्हाइट हाउस के कूटनीतिक आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। वास्तव में अमरीका ने जयवर्द्धने को समझा दिया था कि ऐसा अंतहीन युद्ध लड़ना बेकार है, जहां भारतीय सहयोग के बिना समाधान असंभव हो। इसके साथ-साथ अमरीका श्रीलंका में ट्राटस्की जे०वी०पी० पार्टी के पुनर्जीवित होने से भी सशंकित है। उल्लेखनीय है कि १९७१ में इस पार्टी के उपद्रवों को भी भारतीय मदद से दबाया गया था। सोवियत रूस ने तो उसी समय श्रीलंका में भारतीय भूमिका को हरी झंडी दे दी थी, जब उसने जाफना में तमिलों के लिए राहत सामग्री गिराई थी।

असर : भारत में इस समझौते ने प्रधानमंत्री की फेयरफैक्स और बोफोर्स आदि प्रकरणों से गिरती साख में ठीक समय पर नयी जान फूंकी है। 'गार्ड आफ आनर' के समय उन पर हुए घातक हमले ने उनके प्रति कुछ सहानुभूति भी पैदा की है। भारत ने हमेशा कहा है कि उसने पृथक 'तमिल ईलम' राष्ट्र का समर्थन कभी नहीं किया। वह अपनी सीमा के निकट ऐसे पृथकतावादी आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें उसके अपने प्रांत 'तमिलनाडु' के अलग हो जाने की भी संभावनाएं दिखायी देती है। इसके साथ-साथ चुनावी कारणों से कांग्रेस-इ सरकार दक्षिण भारत में व्याप्त तमिल भावनाओं की न तो उपेक्षा कर सकती है और न ही उससे अलग हो सकती है।

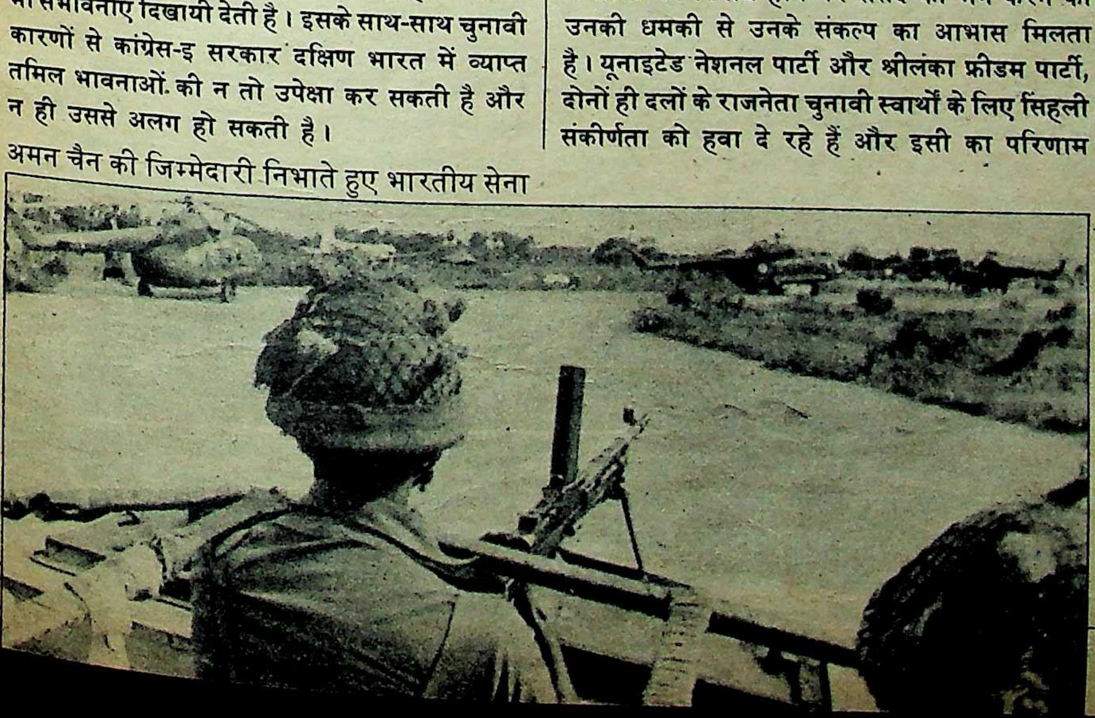

अमन चैन की जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय सेना

क्षेत्रीय स्तर पर इस समझौते से भारत को लाभ पहुंचा है। श्रीलंका में पेशेवर उग्रवादी व इजरायलियों की उपस्थिति और श्रीलंका से पाक के बढ़ते रिश्ते भारत के लिए चिंता का कारण थे। इस बात की भी संभावना थी कि श्रीलंका त्रिकोमाली में अमरीका को नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दे देगा। इस समझौते से ये सारी चिंताएं दूर हो गयी हैं।

आशंकाएं : आशा करनी चाहिए कि राजीव गांधी द्वारा हस्ताक्षर किये गये पंजाब और असम समझौते की तरह यह समझौता खटाई में नहीं पड़ेगा और श्रीलंका में कागजी नहीं, वास्तविक शांति स्थापित हो जायेगी। एल०टी०टी०ई० के उग्रवादी तमिलों ने वहां मौजूद भारतीय सेना के सामने हथियारों का समर्पण करना शुरू कर दिया है। इससे उम्मीद बंधती है कि यह समझौता श्रीलंका में शांति स्थापित करने में कामयाब होगा। लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कुछ उग्रवादी ऐसे भी हो सकते हैं जो हथियार न सौंपें। इसका कारण है, सिंहली सैनिकों का उनके साथ सलूक। सिंहली सैनिकों पर उनका भरोसा नहीं है। आगे यह भरोसा पैदा हो पाता है या नहीं, यह देखना है। वैसे भी यादें जल्दी धुंधली नहीं पड़तीं, न ही पलक झपकते ही घाव भरते हैं। लेकिन हथियार सौंपने की प्रक्रिया संपन्न करने का दायित्व भारतीय सैनिकों पर है—चाहे उन्हें इस काम के लिए अपनी 'शांति स्थापक' राइफिलों का ही उपयोग क्यों न करना पड़े।

राष्ट्रपति जयवर्द्धने के कंधों पर तो और भी ज्यादा भार है। वह ८२ वर्ष के हैं। उनका कार्यकाल भी डेढ़ साल के बाद खतम हो रहा है। लेकिन वह अकेले ऐसे सक्षम राजनेता हैं, जिनका श्रीलंकाई जनता पर असर है। अतः यह उन्हीं पर दारोमदार है कि वह इस समझौते को पूर्णतः क्रियान्वित करें। इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद वह एक राजनेता से नीतिपालक के दर्जे पर पहुंच गये हैं। आशा करनी चाहिए कि वह डी मेल और जैमिनी देशनायके जैसे अपने साथियों की तरह चुनावी दबाव में नहीं आयेंगे।

श्रीलंकाई संविधान को देखते हुए राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वह ऐसे दबावों को सह सकता है। समझौते का विरोध होने पर संसद को भंग करने की उनकी धमकी से उनके संकल्प का आभास मिलता है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, दोनों ही दलों के राजनेता चुनावी स्वार्थों के लिए सिंहली संकीर्णता को हवा दे रहे हैं और इसी का परिणाम है, उत्तरोत्तर बढ़ा वर्तमान संकट। इस समझौते में जयवर्द्धने की निजी भूमिका अहम है। एक प्रकार से यह समझौता दो देशों के बीच न हो कर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच है। इसलिए जयवर्द्धने की उसी तरह की भूमिका है जो पंजाब समझौते में संत लोंगोवाल की थी। अतः जयवर्द्धने को कुछ होता है, तो समझौते का भविष्य अंधकारमय है।

जयवर्द्धने के संभावित उत्तराधिकारियों में प्रेमदास और अथुलथमुदाली का नाम है जो घोषित भारत-विरोधी हैं। प्रेमदास तो कुछ ज्यादा ही भारत विरोधी हैं। श्रीलंका-भारत संबंधों का यह दुर्भाग्य ही है कि नरमपंथियों में गरमपंथी और गरमपंथियों में नरमपंथी माने जाने वाले ललित अथुलथमुदाली जैसे राजनेता भी यह समझते हैं कि भारत-विरोध में ही चुनावी सफलता छिपी है।

सैनिक विद्रोह का खतरा : एक खतरा और है—वह है, सैनिक विद्रोह का। श्रीलंका की सेना का प्रशिक्षण पाकिस्तान में हुआ है और उसने अपनी अलग से सशक्त पहचान बना रखी है। इसलिए विद्रोह के खतरे को निर्मूल नहीं कहा जा सकता। इसे रोकने का तरीका केवल यही है कि भारत यह बात साफ जाहिर करदे कि यदि सैनिक विद्रोह हुआ, तो वह मूकदर्शक बना नहीं रहेगा।

जैसाकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि यह इस सदी का अपनी किस्म का पहला समझौता है, जब किसी दूसरे देश के मामले में भारत ने अपने को प्रत्यक्ष संलग्न किया है और किसी दूसरे देश में शांति स्थापित करने की गारंटी दी है। इससे भारत पर भारी जिम्मेदारी आ गयी है और वह जयवर्द्धने का समर्थन करने के साहसी कदम से पीछे नहीं हट सकता।

इसके साथ ही भारतीय सेना को वापस बुलाने का कार्य भी जल्दी-से-जल्दी करना पड़ेगा। तमिलों के हथियार सौंपने के तुरंत बाद यदि भारतीय सेना के लौटने की स्थितियां बनती हैं, तो सार्क देशों में भारत की छवि निखरेगी, वह एक शक्तिशाली, लेकिन नेकनीयत पड़ोसी माना जायेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो छोटे पड़ोसियों पर अपने बड़े होने की धौंस गालिब करने वाले राष्ट्र के रूप में उसको बदनामी का सामना करना पड़ेगा।

सलामी गारद के समय एक नौसैनिक द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर किये गये हमले से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि द्वीप में शांति स्थापित करने का कार्य कितना कंटकाकीर्ण है। वहां जातीय घृणा को काफी हवा दी गयी है और खासकर पंजाब के नौजवानों की तरह वहां के नौजवान भी इस घृणा के बुरी तरह शिकार बने हुए हैं। इसलिए द्वीप को अखंड और शांत रखने के लिए श्रीलंकाई राजनेताओं पर धैर्य और विवेक से काम लेने की भारी जिम्मेदारी है। देश की जनसंख्या का लगभग आठवां हिस्सा तमिलों की जनसंख्या का है और वे किसी भी हालत में दूसरे दे के नागरिक बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल भारत ही जयवर्द्धने या उनकी जगह जो कोई भी लेता है, की सहायता करके इन तमिलों को लोकतंत्र की मूलधारा से फिर से जोड़कर इस मनोरम द्वीप में शांति और अमन-चैन की स्थापना कर सकता है।

—नंदिता सहगल

राजीव गांधी बाल-बाल बचे

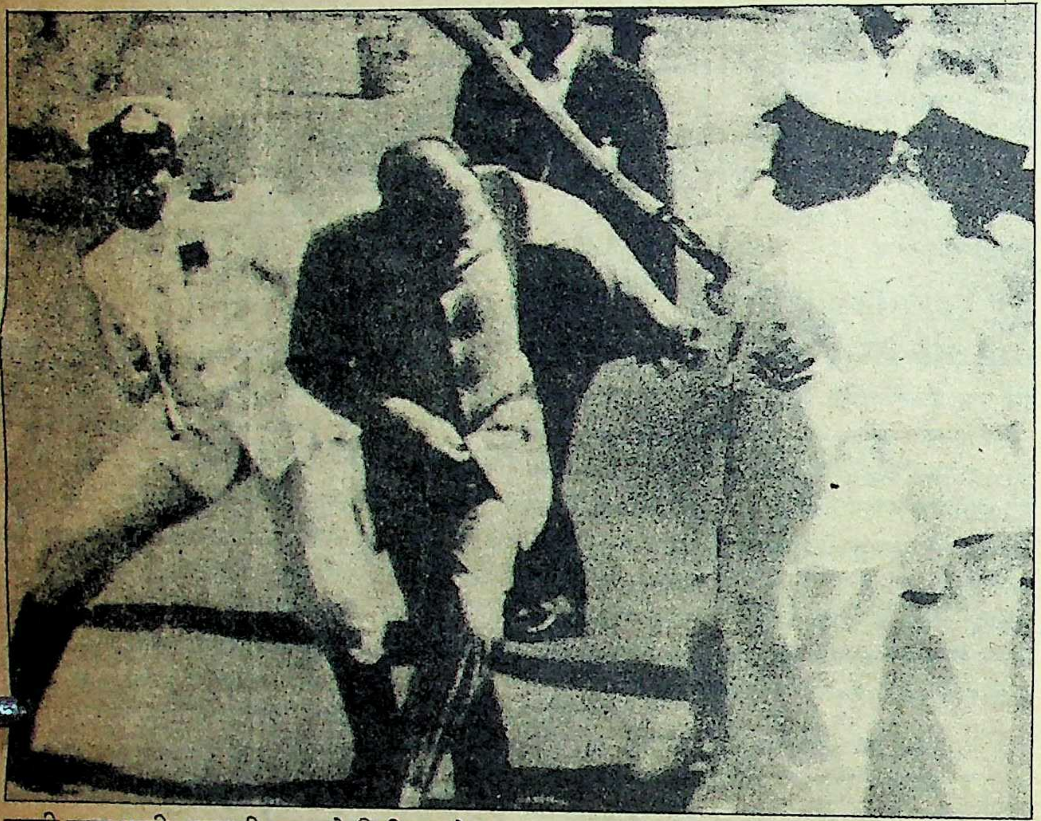

चुस्ती काम आयी : सलामी गारद के निरीक्षण के समय वार

श्रीलंका से शांति समझौता करके विदा होते समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिस प्राणघातक हमले से बाल-बाल बचे, क्या यह एक नौसैनिक की भारत-विरोधी सनक का परिणाम था या इसके पीछे दक्षिण एशिया को अशांत क्षेत्र बनाये रखने में दिलचस्पी रखनेवाली विदेशी शक्तियों का कोई षड्यंत्र था ?

वे क्षण प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीलंका यात्रा के अंतिम क्षण थे। उनके साथ गया पत्रकारों और राजनयिकों का दल समय बचाने के लिए कारों में लद चुका था। श्रीमती सोनिया गांधी विदाई समारोह के समय श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने के साथ सलामी मंच पर खड़ी थीं और राजीव गांधी 'गार्ड आफ आनर' की सलामी गारद का निरीक्षण करते हुए अंतिम छोर तक पहुंच चुके थे, जहां सहसा अंतिम—नौसैनिक के पहले खड़े नौसैनिक ने अपनी रायफल उलटी की, दायां पैर पीछे किया और राजीव गांधी के सिर के पिछले हिस्से पर पूरी ताकत से रायफल की बट से भरपूर वार कर दिया। हमलावर के पैर और रायफल की प्रतिछाया की हलचल को राजीव गांधी ने कनखियों से देखा और सहज प्रकृतिवश उन्होंने अपना सिर आगे की ओर थोड़ा झुका लिया और वह घातक प्रहार गर्दन से रगड़ खाता हुआ उनके कंधे पर आ गिरा। राजीव गांधी की इस अनायास फुर्ती ने उन्हें बचा लिया था। उस समय उनके पीछे विशेष सुरक्षा दल के जी०एस० जामवाल चल रहे थे। हमलावर की रायफल राजीव गांधी के कंधे से फिसलकर अभी जमीन भी नहीं छू पायी थी कि जामवाल ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए हमलावर पर छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी विशेष सुरक्षा दल के अन्य जवान आगे बढ़े, उन्होंने राजीव गांधी को घेर लिया । हमलावर को पकड़कर श्रीलंका की नौसेना-पुलिस को सौंप दिया गया।

यह हमला ३० जुलाई को प्रातः दस बजकर, २० मिनट पर हुआ था। राजीव गांधी ने अद्भुत धैर्य और शांति का परिचय दिया। वह स्थिर भाव से, मानो कुछ हुआ ही न हो, सलामी गारद का निरीक्षण पूरा करके राष्ट्रपति जयवर्द्धने के पास आकर खड़े हो गये। विदाई समारोह का कार्यक्रम समाप्त होते ही वह पत्रकारों और राजनयिकों के दल के साथ वापसी यात्रा पर चल पड़े। क्योंकि यह एक अंतिम औपचारिक कार्यक्रम था, इसलिए वहां फोटोग्राफर मौजूद नहीं थे, लेकिन सारे समारोह की वीडियो रिकार्डिंग हो रही थी और इसी वीडियो टेप के जरिए अपरान्ह तक पूरी दुनिया को राजीव गांधी पर हुए प्राणघातक हमले की प्रत्यक्ष जानकारी हो चुकी थी। वहां गये पत्रकारों के दल को तो स्वयं राजीव गांधी ने वापसी यात्रा पर विमान में पूरी घटना की जानकारी दी। उस समय भी वह संयत थे, यह नहीं लगता था कि यह वही व्यक्ति है, जिस पर कुछ देर पहले प्राणघातक हमला हुआ था, जबकि उनके साथ खड़े मंत्रियो पी० चिदंबरम और के० नटवर सिह के चेहरों पर उस हादसे का खौफ नजर आ रहा था। दिल्ली पहुंचने पर आल इंडिया मेडिकल इस्टीच्यूट में राजीव गांधी का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और उनके कंधे का एक्सरे लिया गया। बायें कंधे पर मामूली चोट के अलावा राजीव गांधी पूर्ण स्वस्थ थे।

राजीव गांधी बाल-बाल बच गये थे। अपनी ही फौज की सलामी लेते हुए मिस्र के राष्ट्रपति सादात को उनकी अपनी ही फौज के सिपाहियों ने गोलियों से भूनकर रख दिया था, लेकिन दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना थी कि 'गार्ड आफ आनर' देती सशस्त्र सैनिक टुकड़ी का कोई जवान विदेशी मेहमान की हत्या का प्रयास करे। यह छोटी घटना नहीं थी। श्रीलंका में भारत के राजदूत जे० एन० दीक्षित ने पत्रकारों को इस घटना के धीमी गति के दृश्य दिखाते हुए बताया, "यदि नौसैनिक की रायफल का बट अपने निशाने (श्री गांधी के सिर के पिछले हिस्से) पर ठीक बैठ जाता, तो उनकी हत्या हो जाती।"

यह तो गनीमत थी कि उस हमलावर नौसैनिक के पास गोलियां नहीं थी, अन्यथा वार बचाना असंभव हो जाता। सादात की हत्या के बाद दुनिया की प्रायः सभी सरकारों ने नियम बना लिया है कि 'गार्ड आफ आर्नर' के समय सलामी गारद को गोली-बारूद न दिया जाये। भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में हथियारों और फौजियों का प्रदर्शन तो होता है, लेकिन उन्हें गोला-बारूद नहीं दिया जाता।

गहरा षड्यंत्र : राजीव गांधी पर प्राणघातक हमला करने वाले नौसैनिक विजितारोहण विजय मुनी से श्रीलंका और भारत के सुरक्षा अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ का ब्यौरा देने से यद्यपि भारत और श्रीलंका के अधिकारियों ने इनकार कर दिया है, लेकिन हमलावर की पूरी शिनाख्त कर ली गयी है। बताया जाता है कि कोलंबो से ११० कि०मी० के फासले पर स्थित बूसा कस्बे का विजय मुनी वहां की 'जनता विमुक्ति पेरामुना' पार्टी का सदस्य था और उसे उस दौरान सेना में भर्ती किया गया था, जब श्रीलंका में तमिलों का सामना करने के लिए सैनिक व अर्धसैनिक संगठनों में अंधाधुंध भर्ती की जा रही थी। उस समय 'पेरामुना' के अनेक सदस्य सेना में भर्ती हो गये थे। विजय मुनी से पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उसका संबंध उन तत्वों से तो नहीं है जो विदेशी गुप्तचर एजेंसियों से मिलकर 'शांति समझौते' का विरोध कर रहे हैं। जांच-अधिकारियों की जांच के परिणामों से असलियत का ठीक-ठीक पता चल सकेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि बिना किसी बड़े षड्यंत्र के एक सामान्य नौसैनिक की इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वह 'गार्ड आफ आनर' के समय विदेशी मेहमान की हत्या करने का प्रयास करे।

वैसे, जब राजीव गांधी श्रीलंका के लिए रवाना हो रहे थे, तो उन्हें संभावित खतरों से आगाह कर दिया गया था। श्रीलंका में हालात बड़ी तेजी से बदले थे। जिस सिंहली उग्रवादी राक्षस पर चढ़कर राष्ट्रपति जयवर्द्धने तमिलों का नरसंहार कर रहे थे और भारत को राहत-सामग्री भेजने तक के लिए आंखें दिखा रहे थे, वही राक्षस जयवर्द्धने को आंखें दिखाने लगा था। जयवर्द्धने को सिंहली सेना में बगावत के आसार साफ-साफ नजर आ रहे थे, जिसने कुछ दिन पहले तक भारत के खिलाफ आग उगलनेवाले जयवर्द्धने को श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारत की मदद लेने पर मजबूर कर दिया था। जयवर्द्धने अच्छी तरह जानते थे कि श्रीलंकाई सेना और सिंहली जनता में उनके खिलाफ असंतोष उभर रहा है, जिसका संकेत उन्हें अप्रैल और जून में कोलंबो के निकट श्रीलंका वायुसेना के अड्डे और सुरक्षा अकादमी पर हुए हमले से मिल गया था, क्योंकि सेना के भीतर से मदद मिले बगैर ये हमले हो ही नहीं सकते थे। इस प्रकार राजीव गांधी इस बार वहां तमिलों के हितों की ही नहीं, बल्कि तमिलों को नष्ट कर देने की घोषणा करनेवाले जयवर्द्धने की भी रक्षा करने गये थे। यही वजह थी कि इधर राजीव गांधी की श्रीलंका यात्रा शुरू हुई, उधर भारतीय सेना के सशस्त्र जवान श्रीलंका में पहुंचने लगे। भारत के दो जंगी जहाज भी कोलंबो के आसपास पहुंचा दिये गये थे। दूसरी ओर जयवर्द्धने ने श्रीलंका के सारे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया था। सारे स्कूल-कालेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिये गये थे। यह महज संयोग नहीं था कि इधर राजीव गांधी पर प्राणघातक हमला हुआ, उधर श्रीलंका के विभिन्न इलाकों में समझौता विरोधी तत्व कर्फ्यू की परवाह किये बिना सड़कों पर निकल आये और समझौता समर्थकों पर चुन-चुन कर हमले करने शुरू कर दिये। उपद्रवकारियों ने जयवर्द्धने समर्थक एक सांसद जिनदास वीरासिंह को उनके वाहन से खींचकर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। उनकी तत्काल मौत हो गयी और उनका घायल पुत्र अस्पताल में भर्ती है। दक्षिणी श्रीलंका के गाल्ले और माटुगामा जिलों में इन उपद्रवकारियों ने चाय-बागान के कर्मचारियों पर हमला कर १४ लोगों को मार डाला। समझौता समर्थक वित्तमंत्री रोन्नेई डी मेल के घर पर हमले हुए। सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि भारत के जो सैनिक और लड़ाकू विमान तमिलों से शस्त्र-समर्पण कराने गये थे, वे वहां राजीव गांधी पर हुए घातक हमले के बाद जयवर्द्धने सरकार और समझौते के विरोध में भड़के उपद्रवों को दबाने में मदद पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। ३० जुलाई को भारतीय वायु सेना के २५ विमान दिनभर उत्तरी श्रीलंका में तैनात श्रीलंकाई फौजियों को उपद्रवों को दबाने के लिए श्रीलंका के दक्षिणी इलाकों में पहुंचाते रहे। इसे संयोग नहीं कहा जा सकता कि इधर भारत-श्रीलंका समझौते ने श्रीलंका से पाकिस्तानी और इजरायली सलाहकारों का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया, और त्रिकोमाली में अमरीकी अड्डे की संभावनाएं समाप्त कर दीं, तो उधर अमरीका ने भारत को इजरायल से सम्पर्क बढ़ाने की सलाह देते हुए भारत को दी जानेवाली सहायता राशि में रोक लगा दी। समझौता समर्थक वित्तमंत्री रोन्नेई डी मेल ने तो राजीव गांधी पर हुए हमले के लिए राष्ट्रीय सुरक्षामंत्री ललिथ अथुलाथमुदाली को दोषी ठहराते हुए, उनसे त्याग पत्र की मांग की है। श्री अथुलाथमुदाली के विदेशी संपर्कों पर भी सवाल उठाये गये हैं? वह जेरूसलम विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रह चुके हैं और उन्हीं के इजरायली सम्पर्कों की बदौलत श्रीलंकाई गुप्तचर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए १९८४ से इजरायली प्रशिक्षकों का श्रीलंका आना शुरू हो गया था। इन कारणों से ही इशारा किया जा रहा है कि राजीव गांधी पर हुए हमले के पीछे सी०आई०ए० का हाथ हो सकता है। पं० बंगाल युवा कांग्रेस-इ ने तो स्पष्ट रूप से इस हादसे के लिए सी०आई०ए० को जिम्मेदार ठहराया है। यद्यपि जयवर्द्धने ने शुरू-शुरू में इस घटना पर लीपापोती करते हुए कहा था कि धूप से चक्कर आ जाने के कारण उस नौसैनिक की रायफल उसके हाथ से छिटककर राजीव गांधी को लग गयी है, लेकिन असलियत से वाकिफ होते ही बताया जाता है कि उन्होंने स्वदेश रवाना होते समय राजीव गांधी से कहा था, "ईश्वर ने आपको बचा लिया, ईश्वर आपको लम्बी उम्र दें।"

शांति सेना : 'भारतीय सैनिक' पलाली हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए

भारत में प्रतिक्रिया : पिछले दस मास में यह दूसरा वाकया है, जिसमें प्रधानमंत्री की जान लेने की कोशिश की गयी। गत वर्ष २ अक्तूबर को गांधी समाधि पर एक सिख आतंकवादी ने घात लगाकर राजीव गांधी पर गोलियां चलाई थीं, लेकिन उसका निशाना चूक गया था। इस बार भी वह दैवयोग और अपनी त्वरित बुद्धि के कारण बच गये। राजीव गांधी पर हुए हमले की खबर से सारे भारतवासी सकते में आ गये। अधिकांश मंत्री और सांसद उस वक्त संसद भवन के सेंट्रल हाल में थे। सांसद टाइटलर के अनुसार, "यह खबर सुनते ही अनेक सांसद और मंत्री तो वास्तव में सुबक पड़े थे।"

दिल्ली को इसकी पहली खबर १० बजकर, ४६ मिनट पर ही मिल गयी थी। इस खबर के साथ दिल्ली में आतंक भी फैल गया। यह अफवाह उड़ी कि शायद राजीव गांधी की हत्या हो गयी है। कई बाजार धड़ाधड़ बन्द हो गये। बम्बई में भी ऐसा ही आतंक फैला, लेकिन शाम के दूरदर्शन समाचार बुलेटिन से सारी बात साफ हो गयी और लोगों ने राहत की सांस ली कि "प्रधान-मंत्री बच गये हैं।'

दिल्ली हवाई अड्डे पर राजीव गांधी का सांसदों मंत्रियों और शुभचिंतकों ने भाव-विभोर होकर आत्मीय अभिनंदन किया। इस शांति-समझौते से पूरी दुनिया में राजीव गांधी और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन जिस धैर्य और सूझबूझ से उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का सामना किया, उससे भारतवासियों को 'विपत्तियों में अविचलित रहनेवाली' उनकी एक सर्वथा नयी छवि के दर्शन हुए हैं। जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से उनके खून के प्यासे सिख आतंकवादी मौके की तलाश में हैं। मौत का साया उन पर और उनके पूरे परिवार पर हर वक्त मंडराता रहता है। श्रीलंका में हुए हादसे से एक बार फिर उनके प्रति पूरे देश में सहानुभूति पैदा हो गयी है। उनकी दीर्घायु के लिए मंदिरों में महा-मृत्युंजय जाप कराया जा रहा है, विश्व के राष्ट्रनेताओं ने श्री गांधी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए इस घटना की निंदा की है। भारत के पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं ने राजीव गांधी के दीर्घायु होने की कामना की। राष्ट्रपति वेंकटरमण का कहना था, "शांति के रास्ते में ऐसी ही बाधाएं आती हैं।"

—विनोद मिश्र और ब्यूरो रिपोर्ट

मेरठ

सांप्रदायिकता का स्थायी केंद्र क्यों बना ?

दंगे की असलियत : १९ मई को हापुड़ रोड पर दंगाइयों द्वारा जलायी गयीं दुकानें

> १४ अप्रैल, १९८७ से किसी-न-किसी बहाने मेरठ जिला दंगे की चपेट में है। ये बहाने बताते हैं कि हर दंगे के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र है। जिस मेरठ के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के परखचे उड़ा दिये थे, आज वही शहर सांप्रदायिकता के लाइलाज रोग से ग्रस्त क्यों है ?

लगातार चार महीनों से सांप्रदायिकता की आग में जल रहे मेरठ में अभी भी लपटें थमती नजर नहीं आ रही हैं। भय और आशंका में डूबे इस शहर में कब क्या हो जाये। कुछ पता नहीं। किसी साइकिल का टायर फटने की आवाज भी यहां के लोगों को बम के धमाके जैसी लगती है। साधारण सी बात को लेकर चाकू से लेकर बमबारी तक की घटना अब यहां के लिए आम बात हो गयी है।

यहां के अनेक ओहदेदारों की अदला-बदली के बावजूद वीर बहादुर की सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस सबसे संपन्न जिले में पुनः शांति स्थापित करने में पूर्णतया असफल रही है। अब सवाल यह नहीं है कि दंगे मेरठ की नियति बन चुके हैं, चिंता तो दंगे के उस स्वरूप को लेकर है जो २२ जुलाई की रात्रि को सामने आया है। यह घटना ठीक उसी तरह की है, जैसी पंजाब में आम तौर पर हो रही हैं।

सांप्रदायिकता का घिनौना रूप : **मेरठ शहर से ३० किलोमीटर दूर पुरामहादेव का मंदिर है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष साव्वन के महीने में दूरदराज से शिवभक्त आकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं। हरिद्वार से गंगाजल कांवर में लादकर हजारों की संख्या में कांवरिये १५० किलोमीटर की लंबी यात्रा 'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ पूरी कर पुरामहादेव पहुंचते हैं और वहां भोलेशंकर पर गंगाजल अर्पित करते हैं।**

२१ जुलाई को किसी ने अफवाह फैला दी कि मुजफ्फरनगर के पास मुसलमानों ने दो कांवरियों की हत्या करके लाश नदी में फेंक दी है। बस, इन शिव भक्तों का तांडव शुरू हो गया। प्रमुख मार्गों पर आने-जाने वाले वाहनों पर कांवरियों के समूह ने पथराव किया। इसी बीच कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने कांवरियों को साथ लेकर २२ जुलाई की रात्रि करीब ११ बजे दारौलासकौती कस्बे के मध्य रोडवेज की दो बसों को रोक लिया। ऐसा नहीं है कि सभी कांवरियों पर सांप्रदायिकता का जुनून छाया हुआ था, लेकिन संजीदा लोग उस समय मचे हड़कंप में बेबस थे। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था ।

कुछ कांवरियों ने बंस में चढ़कर यात्रियों के नाम पूछे और एक खास समुदाय के यात्रियों को जबरन नीचे उतार लिया गया। फिर डंडों तथा लोहे की छड़ों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पिटते यात्रियों को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर भाग चुके थे। कराहते सात यात्री, जिनमें तीन महिलाएं भी थीं, मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को मेरठ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मृत्यु हो गयी।

यू०जी०ओ० ९८८३ नम्बर की एक सरकारी

बस हरिद्वार से बिजनौर जा रही थी। कुछ घायल यात्री, भयवश मेरठ जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वे दूसरी बस पर सवार होकर अपने घर चले गये। इनमें से एक की मौत बिजनौर के जिला अस्पताल में हो गयी। इस हादसे की सूचना जब बिजनौर पहुंची, तो वहां भी जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया।

साजिश : दरअसल, यह सब कांवरियों को भड़काकर, उनकी आड़ में दंगे को खतरनाक मोड़ देने की साजिश के तहत हुआ था। २१ जुलाई को ही कुछ लोगों ने अफवाहों के आधार पर कांवरियों को भड़काने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हरिद्वार से पुरामहादेव की ओर जा रहे कांवरियों के झुंड को रास्ते में कुछ लोग यह बता रहे थे, 'संभल कर जाना, मुजफ्फरनगर में में दो कांवरियों की मुसलमानों ने हत्या कर दी है।' यह अफवाह इस ढंग से फैलायी गयी कि कांवरियों को विश्वास हो गया। इस विश्वास का एक कारण और भी था। पिछले वर्ष मेरठ के ही बरनावा कस्बे में किसी शरारती तत्व ने एक कांवरिये की कांवर में मांस का टुकड़ा रख दिया था। तब भी दंगा हुआ था। उस दंगे में जिला प्रशासन ने कांवरियों की ही पिटायी की थी।

कुछ कांवरिये तो इस बार यह तय करके आये थे कि पिछली बार उनके साथ जो कुछ हुआ था, उसका बदला इस बार वे जरूर लेंगे। यही वजह थी कि जब मुजफ्फरनगर से १२ किलोमीटर दूर मेरठ मार्ग पर मंसूरपुर कस्बे के निकट कांवरियों का एक झुंड विश्राम कर रहा था, तब किसी ने यह अफवाह फैला दी कि किसी कांवरिये को एक मुसलमान पकड़कर अपने बाग में ले गया है और वहां उसकी हत्या कर दी है। इस अफवाह में कोई सत्यता नहीं थी। लेकिन जो लोग बदला लेने के लिए तय करके आये थे, उन्होंने 'बम-बम भोले' की आवाज के साथ सड़क से गुजरने वाले वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। पेड़ की शाखाएं तोड़कर सड़क पर डाल दीं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। यह तो गनीमत थी कि सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र नाथ सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गये और स्थिति बिगड़ने से बचा ली।

मंसूरनगर की इस घटना को मेरठ में तूल देकर फैलाया गया। वहां यह बताया गया कि मंसूरनगर में दो कांवरियों को मार कर उनकी लाशें नाले में फेंक दी गयीं हैं। दादरी में कांवरियों के झुंड को जब इस अफवाह का पता चला, तो उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली जा रही बस को जबरन रुकवा लिया। उसमें सवार कई यात्रियों के नाम पूछकर उनको नीचे उतारा और पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। खतौली निवासी एक व्यक्ति ने मृत होने का बहाना रच कर किसी प्रकार अपनी जान बचायी। चार लोगों की मौके पर ही ही मृत्यु हो गयी।

यह घटना २२ जुलाई की शाम ५-६ बजे के आस-पास की थी। इसके बाद पुलिस की सतर्कता और चौकसी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। नतीजतन उसी रात ११ बजे दारौला के पास इसी शैली में ६ यात्रियों को और मार डाला गया।

इस वारदात के बाद दंगे की आग दूर-दराज तक फैल गयी। बागपत तहसील के सरूरपुर गांव में उत्तेजित भीड़ पर पुलिस ने फार्यारिंग की। जिसमें दो लोग मौके पर मारे गये। मेरठ शहर में एक बार फिर कर्फ्यू सख्त कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चौथी बार सेना की सहायता ली गयी।

मेरठ में ऐसा क्यों : सवाल उठता है कि आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि मेरठ में दंगे नहीं रुक पा रहे हैं? आज मेरठ में पंजाब जैसी स्थिति क्यों हो गयी है? क्या मेरठवासियों को कर्फ्यू के दौरान बजबजाती नालियों, विषाक्त वातावरण, सैनिक और अर्धसैनिक बलों के फ्लैग मार्च तथा निरीह लोगों की हत्याओं से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी?

इस सारे प्रकरण के लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक दयाशंकर भटनागर प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप को जिम्मेदार मानते हैं। मेरठ दंगे के कारण वीर बहादुर सिंह ने दयाशंकर भटनागर जैसे सख्त अफसर को अपमानजनक तरीके से पुलिस महानिदेशक पद से हटाया था। श्री भटनागर ने इस सिलसिले में ५० पृष्ठों की एक रिपोर्ट शासन को भेजते हुए उन कारणों को उजागर किया है, जिनकी वजह से आज मेरठ दंगों का केन्द्र बन गया है। भीतरी सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में दंगा न रुकने का मुख्य कारण उन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवायी न होना है, जिन्होंने दंगे के दौरान बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था।

इस वर्ष १४ अप्रैल को शबेबारात के मौके पर जब मेरठ में दंगा भड़का था, तब एक उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की गयी थी। बैठक में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री पी० चिदम्बरम, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक दयाशंकर भटनागर, गृहसचिव माता प्रसाद और पुलिस महानिरीक्षक (अभिसूचना) टी०एस० विष्ट थे। उस समय यह निर्णय लिया गया कि यदि भविष्य में फिर दंगे के आसार नजर आयें, तो सबसे पहले सांप्रदायिक गुंडों की गिरफ्तारी की जाये। ऐसे गुंडों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी गुप्तचर विभाग को सौंपी गयी।

दंगे में मृत डा० प्रभात सिंह की पत्नी और बच्चे

गुप्तचर विभाग ने १३६ ऐसे गुंडों की सूची तैयार कर ३० अप्रैल तक गृह मंत्रालय को भेज दी थी जो मेरठ की शांति के लिए खतरा थे। इनमें वे तत्व भी थे, जिन्होंने १४ अप्रैल को दंगा कराया था। दो दिनों बाद ही गृह मंत्रालय ने यह सूची मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास इस निर्देश के साथ भेज दी थी कि इन तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये तथा आवश्यक समझा जाये, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाये।

यह पुलिस की लापरवाही थी या किसी राजनीतिक शक्ति की चाल कि १८ मई को दुबारा भड़के दंगे के बाद जो २५० लोग गिरफ्तार किये गये, उनमें जासूसी विभाग द्वारा तैयार की गयी सूची का एक व्यक्ति भी नहीं था। यही नहीं, १४ अप्रैल के दंगे के दौरान जिन १५० लोगों को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा करते रंगे हाथों पकड़ा गया था, उन्हें भी दूसरा दंगा होने से पहले ही 'सम्मान' रिहा कर दिया गया था। इनकी रिहाई के लिए अदालत में सरकारी वकील मसर्रत अली ने दलील पेश की थी, "अब दंगा खतम हो गया है, इसलिए सरकार को इनकी रिहाई पर कोई एतराज नहीं है।"

१८ मई के दूसरे दंगे के बाद पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, डी०आई०जी०, एस०एस०पी० को जिम्मेदार मानते हुए वीर बहादुर ने हटा तो दिया, लेकिन दंगे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जिलाधिकारी राधेश्याम कौशिक को तब हटाया गया, जब लगातार दो बार और दंगा भड़का। कौशिक को न हटाने का एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि उन्हें केन्द्रीय मंत्री तथा मेरठ की सांसद मोहसिना किदवई का वरदहस्त प्राप्त था। यही नहीं, मोहसिना किदवई के ही एक कथित चहेते अधिकारी नाथूलाल को, दंगे के लिए जिम्मेदार मानते हुए डी०डी०आई०जी० के पद से हटाया तो गया, लेकिन उन्हें हटाने के तत्काल बाद ही आई०जी० बनाकर पुरस्कृत कर दिया गया। यह भी एक विडम्बना ही थी कि जिन पुलिस महानिदेशक, दयाशंकर भटनागर ने आठ दिन तक मेरठ में कैम्प कर दंगे को नियंत्रित किया था, उन्हें पद से हटाकर अपमानित किया गया।

अब उन्हीं भटनागर की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। सरकार इस रिपोर्ट को इसलिए प्रकाशित नहीं कर है, क्योंकि उससे ऐसे तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे जो शासन में बैठकर दंगे की आग में अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेंक रहे हैं।

प्रशासनिक अदूरदर्शिता : १८ मई के बड़े दंगे और उसके बाद की दर्जनों छिटपुट घटनाओं के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटते मेरठ शहर में जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता ने फिर विघ्न डाल दिया।

सियासी फिरकापरस्तों की चालें हैं : जैनुर आबेदीन

२८ जून को मेरठ में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलनी थी। जिला प्रशासन ने रथयात्रा आयोजकों से बातचीत के बाद यात्रा का मार्ग और उसमें शामिल लोगों की संख्या तय कर दी थी। लेकिन ऐन मौके पर यात्रा प्रतिबंधित कर दी गयी। नतीजतन फिर दंगा भड़का। हारकर २ जुलाई को रथयात्रा की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गयी। किन्तु तब तक काफी देर हो चुकी थी। शहर में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की पुनरावृत्ति हुई, जिसमें पांच लोगों की जानें गयीं।

२ जुलाई को यद्यपि रथयात्रा शान्तिपूर्वक निकली, लेकिन पहले जहां चार-पांच सौ लोग उसमें शामिल होते थे, इस बार यह संख्या पचास हजार तक पहुंच गयी थी। यह सब जिलाधिकारी राधेश्याम कौशिक की अदूरदर्शिता का नतीजा था। इस बार भड़के दंगे से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जिलाधिकारी के विरुद्ध आक्रोश फूट पड़ा। फसादों का सिलसिला चल ही रहा था, फलत: ४ जुलाई को उन्हें पद से हटाया गया।

उनके हटने से मेरठ शान्त हो गया था, ऐसी बात भी नहीं। इसका एक कारण था कि मेरठ प्रशासन पर शुरू से चले आ रहे राजनीतिक हस्तक्षेप में 'ब्रेक' नहीं लग पा रहा था। फलस्वरूप १५ जुलाई को फिर दंगा भड़का। जिनमें पांच जानें चली गयीं। उस दिन बजाजा मोहल्ले में एक कबाड़ी के यहां बम विस्फोट के बाद भड़की सांप्रदायिकता ने पांच जानें ले ली थीं।

तीसरे ही दिन १८ जुलाई को गुदड़ी बाजार में सांप्रदायिक विद्वेष से भरे लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। हिंसा पर उतारू भीड़ पर पुलिस ने गोली चलायी, जिसमें दो लोग मारे गये।

ताज्जुब की बात तो यह है कि जिला प्रशासन कुछ धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकरों से उगले जा रहे जहर को नहीं रोक पाया है जो आग में घी का काम कर रहा है। इन लाउडस्पीकरों पर कहा जा रहा है : "कौम खतरे में है, उसकी हिफाजत के लिए सड़क पर आओ।" प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्फ्यू और सख्ती के बावजूद स्वामी मुक्तिबोध और शहाबुद्दीन जैसे कट्टरपंथी लोग मेरठ में बेरोकटोक आते हैं और सांप्रदायिकता का जहर उगल कर चले जाते हैं। २२ जुलाई को तो कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने भी मेरठ पहुंचने की योजना बनायी थी। लेकिन वीर बहादुर सिंह के हाथ-पैर जोड़ने पर उन्होंने मेरठ जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। फारूख को सांप्रदायिक नहीं माना जा सकता। फिर उनको जाने से क्यों रोका ? क्या उनके वहां जाने से मेरठ में प्रशासनिक गफलतों का और भंडाफोड़ होने का डर था ?

सरकार और प्रशासन की इन्हीं खामियों की वजह से मेरठ में सांप्रदायिक ताकतों की साजिशें लगातार कामयाब हो रही हैं। नहीं तो क्या वजह है कि पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले उर्दू अखबार 'पाकिस्तान टाइम्स' और 'अखबार-ए-नौ' की प्रतियां अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में गुप्तरूप से वितरित होती हैं। इन अखबारों में मेरठ दंगों की उलटी-सीधी खबरें शाया हो रही हैं। शायद इसीलिए हकीकत की जानकारी करने हेतु पाकिस्तान में भारत के राजदूत शैलेन्द्र कुमार सिंह को मेरठ का दौरा करना पड़ा।

हताहत : जले हुए मकान फुंकी हुई दुकानों, खिड़कियों की ओट से झांकते मायूस चेहरों पर दहशत के स्थिर भाव, दंगे की त्रासदी का खुलासा करते हैं। जिला प्रशासन दंगे से मारे गये लोगों की संख्या १०० बताता है। इनमें १४ की अभी भी शिनाख्त नहीं हुई है। इनमें ७ शव तो ऐसे थे, जिनके बारे में यही पता नहीं चल सका कि वे पुरुष थे या स्त्री ? शहर के १४९ लापता लोगों के बारे में भी प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले सका है। चार माह से गायब इन लोगों को प्रशासन ने न तो मृतकों में गिना है और न ही उनके परिवारवालों को मुआवजे की सूची में रखा है। अनिश्चितता की इस स्थिति में उनके परिजन दोहरी मार के शिकार हो रहे हैं।

हाशिमपुरा के लोगों ने ३६ ऐसे व्यक्तियों की सूची दी है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें अर्धसैनिक बलों द्वारा मार कर हिंडन नदी में फेंका गया है। इस सूची का एक भी नाम प्रशासन की किसी भी सूची में नहीं है। इस सूची के बारे में हाशिमपुरा के निवासियों का कहना है कि २२ मई की दोपहर पी०ए०सी० वाले इन लोगों को पकड़ कर मुरादनगर (गाजियाबाद) के अबूपुर गांव ले गये, जहां उन्हें गोली से उड़ा दिया। लाशें हिंडन नदी में फेंक दीं। यही लाशें अगले दिन गाजियाबाद पुलिस ने बरामद की थीं।

हाशिमपुरा के बगीचा मोहम्मद हुसैन में रहनेवाले जलालुद्दीन बताते हैं, "जिन लोगों को पुलिस पकड़कर ले गयी थी, उनमें मेरा बेटा कमरुद्दीन भी था। गाजियाबाद जाकर मैंने उसकी लाश की शिनाख्त की और वहां रिपोर्ट दर्ज करायी, लेकिन फिर भी सरकार उसे मरा नहीं मानती।" जलालुद्दीन थर्राये स्वर में कहते हैं, "बेटा तो गया ही, अब मुआवजे से भी मारा जा रहा है।" जलालुद्दीन अपने इस कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं देते हैं। गाजियाबाद में उन्होंने क्या रिपोर्ट दर्ज करायी थी, इस बारे में वह साफ-साफ कुछ नहीं बताते हैं। हाशिमपुरा के लोगों द्वारा तैयार की गयी

मेरठ दंगों का रोजनामचा

तारीख	स्थान	कारण	मृतकों की संख्या
१४ अप्रैल, १९८७	शाहपीर गेट तथा आसपास का इलाका	शब-ए-बारात पर आतिशबाजी विवाद	१३
१७ मई से १७ जून, १९८७ के मध्य	छीपीबाड़ा, पिलोखड़ी रोड, हाशिमपुरा, शास्त्रीनगर ट्रांसपोर्ट नगर सहित पूरे मेरठ शहर में	अजय शर्मा की हत्या के बाद भड़की हिंसा,	७५
२३ मई, १९८७	मलियाना (मेरठ का ग्रामीण क्षेत्र)	पी०ए०सी० वालों की गोली से	
२५ मई, १९८७	हिंडन नदी (गाजियाबाद)	आरोप है कि अर्धसैनिक बल के लोगों ने हत्या के बाद लाशें फेंकीं	१६
२६ मई, १९८७	शास्त्रीनगर सेक्टर-४	जिन्दा जलाया गया	३
२८ से ३० जून, १९८७	दिल्ली गेट थाने के बेली बाजार में	रथयात्रा पर रोक से भड़की हिंसा	५
१५ जुलाई, १९८७	बजाजा बाजार	कबाड़ी के यहां बम विस्फोट	५
१८ जुलाई, १९८७	गुदड़ी बाजार	हिंसक भीड़ पर पुलिस फायरिंग	२
२२ जुलाई, १९८७	घासीपुर (मुजफ्फरनगर) सकौती-दौराला तथा मंसूरपुर	बस और कार से उतार कर यात्रियों की हत्या	११
२४ जुलाई, १९८७	सरूरपुर कलां	छात्रों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग	२

योग— १५०

सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक १ जनवरी, १९८६ से २५ जुलाई, १९८७ के मध्य उत्तर प्रदेश के १७ जिलों में सांप्रदायिक दंगों की ३५ घटनाएं हुईं, जिनमें २९५ लोग मारे गये। मार्च, १९८६ में मेरठ में हुए दंगे में २३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

—राजेन्द्र कुमार

सूची में वे नाम भी हैं जो अब जिन्दा मिल गये हैं। इनमें जुल्फिकार नासिर, नईम आरिफ, उस्मान, मुजीबुर्रहमान तथा बाबूदीन हैं। ये सभी जख्मी हालत में पुलिस द्वारा पकड़े गये थे। इन्हीं लोगों की चश्मदीद गवाही पर गंगानहर में मिली लाशें अब प्रशासन के गले की हड्डी बन गयी हैं।

इन्हीं घायलों में से एक उस्मान, सरकारी खर्च पर इलाज करवाकर वापस आ गया है, लेकिन वह कहां है? कोई नहीं बताता। उसके वालिद बशीर अहमद कहते हैं, "२२ मई की दोपहर पकड़े जाने वालों में उस्मान भी था। गाजियाबाद में उसके जख्मी हालत में पाये जाने की सूचना पाकर मैं वहां गया था। सरकार ने ही उसका दिल्ली में इलाज कराया था। चूंकि वह घटना का चश्मदीद गवाह है, उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसकी मौजूदगी की जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। बशीर अहमद का आरोप है, "दंगाइयों ने घर में आग लगायी थी। मेरे ८० वर्षीय वालिद अब्दुल मजीद को गोली लगी, वह मर गये। मुआवजे की रकम इस हिसाब से काफी कम है।"

दंगे की आड़ में लोगों को आपसी रंजिश निभाने का भी खूब मौका मिल रहा है। कुछ घटनाएं आपसी रंजिश के कारण हुई और आरोप दूसरे संप्रदाय पर थोपा गया। इनमें कुछ तो पकड़े गये। बाकी साफ बच निकले। दरअसल, दंगे की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। १७ मई की रात्रि सूरजकुण्ड मोहल्ले के जिस खोखे में लगी आग ने पूरे मेरठ को अपनी लपेट में ले लिया था, वह खोखा हिंदू का था। एक मुसलमान ने उसे किराये पर ले रखा था। उस खोखे को मोहम्मद उमर नामक दूसरा व्यक्ति किराये पर लेना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में ठनी हुई थी। उस दिन मौका देखकर मोहम्मद उमर ने खोखे में आग लगा दी थी। दंगे के दौरान शास्त्री नगर के सेक्टर चार निवासी ४५ वर्षीय सुनील की हत्या हुई। आरोप दूसरे संप्रदाय पर डाला गया। बाद में पता चला कि उसी की पत्नी ने अपने दो भाइयों की मदद से यह हत्या की थी। तीनों गिरफ्तार हुए। डालमपाड़ा मोहल्ले में अनिल जैन और किरायेदार चंद्र दत्त त्रिपाठी में मकान खाली कराने का झगड़ा था। दंगे की आड़ में त्रिपाठी की हत्या हुई। बात सांप्रदायिकता तक पहुंचती, इसके पहले ही अनिल जैन पकड़ में आ गया। इब्राहिम ने खुद को कैंची से घायल कर रंजिश में दूसरे को फंसाना चाहा, लेकिन पकड़ा गया।

जान की कीमत : बहरहाल, इस समय मेरठ में एक जान की सरकारी कीमत २० हजार रुपए है। किसी की मौत हो और अगर साथ में 'दंगा' शब्द जुड़ जाये, तो मरनेवाले के परिवार को २० हजार नकद मिल जायेंगे। २० जुलाई तक २ करोड़ २० लाख रुपए का ऐसा ही मुआवजा बांटा जा चुका था। मुआवजे के बढ़ते दावेदारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकार से इस मद में रकम बढ़ाने की मांग की है।

मुआवजे की इस भीड़ में तमाम ऐसे भी हैं, जिनकी मांगें फर्जी हैं। प्रशासन को २० जुलाई तक मुआवजे के लिए जो ४८१२ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें ३५४० की जांच के दौरान २७६० ऐसे पाये गये, जिनका दंगे में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

व्यापार चौपट हो गया है : ओ०पी० खन्ना

इसके विपरीत सूरजकुण्ड निवासी प्रभात कुमार शर्मा की दंगे के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उनके भाई मेजर सतीश शर्मा कहते हैं, "हम मुआवजा लेना नहीं चाहते थे। जिलाधिकारी ने चेक भिजवा दिया। अब इन पैसों को किसी ऐसे अनाथ बच्चे पर खर्च करेंगे, जिसके मां-बाप दंगे की बलि चढ़े हैं।"

डाक्टर हरपाल सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री सिंह दोनों अध्यापक हैं। १८ मई को उनके पुत्र डाक्टर प्रभात सिंह को दंगाइयों ने उनकी कार में ही जलाकर मार डाला था। डाक्टर हरपाल सिंह बताते हैं, "मेरा परिवार धर्म निरपेक्ष है। १९८२ के दंगे में मैंने अल्पसंख्यकों के हित के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इस दंगे ने हमारी इस भावना पर कुठाराघात कर दिया है।" डाक्टर प्रभात के मित्रों ने प्रभात स्मारक बनाकर गरीबों की मुफ्त चिकित्सा की घोषणा की है।

आर्थिक क्षति : दंगे में सबसे ज्यादा क्षति यहां के व्यापारी वर्ग को हुई है। दुकान और प्रतिष्ठान ही लूट, तोड़फोड़ और आगजनी का शिकार बने हैं। दंगे ने बड़े व्यापारियों को तो तबाह किया ही है, छोटी पूंजी वाले व्यापारी भी दंगे की मार से उठ नहीं पा रहे हैं। संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री ओ०पी० खन्ना का कहना है, "दंगे के कारण व्यापारिक क्षति अब तक १०० करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यहां सूत, खादी कपड़ों की प्रिन्टिंग तथा कैंची का प्रतिदिन १०० से १५० करोड़ रुपए का व्यापार होता था जो पिछले चार महीनों से ठप पड़ा है। जिन व्यापारियों का लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उन्हें मात्र १० से १५ हजार रुपए दिये गये हैं। लगभग ३० प्रतिशत व्यापारियों ने ही बीमा करा रखा था। अभी तक किसी भी बीमा कम्पनी से पैसा नहीं मिला है।" खन्ना का आरोप है, "अल्पसंख्यकों को मुआवजा देने में प्रशासन की नीति काफी उदार है। लेकिन बहुसंख्यकों को बहुत दौड़-भाग करनी पड़ रही है।"

दंगे में मारे गये लोगों के परिवारजनों के आंसू अभी थमें नहीं हैं। कर्फ्यू का सन्नाटा और घर में मातमी माहौल के बीच रात-दिन अपनी औलाद या मां-बाप की याद में कट रहे हैं। आपसी सौहार्द को सांप्रदायिकता की आग ने भस्म कर दिया है। बागपत क्षेत्र के विधायक कोकब हमीद इस माहौल का इस तरह बयान करते हैं, "दंगे अब इस शहर की शुरुआत की नियति बन चुके हैं। दंगे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार उसका मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। पहले, दंगे के बाद एक तबके के लोग दूसरे से गले मिलकर शिकवे-शिकायतें मिटा लिया करते थे। अब तो दिलमैली ने हद कर दी है। एक साथ पले-बढ़े लोग एक दूसरे से चाह कर भी मिलने में खौफ खाने लगे हैं।"

मेरठ शहर के इंका विधायक राजेन्द्र शर्मा बताते हैं, "मेरठ के बदले माहौल को देखकर अब यह शक होने लगा है कि क्या यह वही शहर है, जहां हिन्दू-मुसलमानों ने एक जुट होकर अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। स्वाधीनता आन्दोलन का श्रीगणेश करनेवाले मेरठ को इस हालत में पहुंचाने के लिए सत्ता के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को डूब मरना चाहिए।"

जैनुर आबेदीन मेरठ के शहरकाजी हैं। दोनों तबकों के लोग उनकी खासी इज्जत करते हैं। फिरकापरस्तों से उनकी कभी नहीं पटी। अशान्त मेरठ के बारे में वह कहते हैं, "यह सब सियासी फिरकापरस्तों की चालें हैं। दंगों में मारकाट करनेवाले गुंडों के सरपरस्तों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। केवल अफसरों के तबादलों से कुछ नहीं होना है। जरूरत है, आवाम के दिलों की नफरत को भाई-चारे में तब्दील करने की।" अलीगढ़ विश्वविद्यालय में रीडर शहरकाजी के एक पुत्र का आरोप है, "कौमी सियासत ही दंगे की बुनियाद है। मेरठ में अब बयानों का दंगा चल रहा है। एक दूसरे के पास जाकर दिलमैली साफ करने की अहमियत को दरकिनार कर दिया गया है। पुलिस या सेना के बल पर दंगे की आग बुझाई नहीं जा सकती है।"

मेरठ के दंगे के मसले पर बयानबाजी करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन इन बयानबाजों में एक भी ऐसा नहीं है जो दूसरे मजहब के लोगों के बीच जाकर सद्भावना पैदा करने की उदारता दिखा सके। ऊपरी तौर पर एकता का राग अलापने वाले दिली तौर पर सांप्रदायिक हैं। इसकी मिसाल, फिरकापरस्तों के खिलाफ बोलनेवाले शहरकाजी के ही मकान में मिलती है। उनके एक साहबजादे इंका के जिला मंत्री हैं। इसी १८ जुलाई को गुदड़ी बाजार में दंगे के दौरान उपद्रवकारियों का नेतृत्व करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। यह दीगर बात है कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। अब लोग कहते हैं, "जब शहरकाजी अपनी औलाद को नहीं समझ सकते, तो दूसरों को क्या नसीहत देंगे।"

शहर में शांति समितियों के गठन की प्रक्रिया जोरों पर है। लेकिन आरोप है कि ये समितियां केवल नाम के लिए हैं। समिति के सदस्यों की गतिशीलता केवल अधिकारियों के चाय-पानी तक ही सीमित है।

मेरठ के मौजूदा हालात यह बताते हैं कि सेना और पुलिस के बल पर शान्ति और सद्भाव का वातावरण नहीं बन सकता है। जरूरत है राजनीतिक चेतना की।

—मेरठ से सुरेश द्विवेदी और राजेन्द्र कुमार

वीर बहादुर सिंह

पुनर्जीवन

इलाहाबाद में एक अगस्त को सरकारी साधनों के बल पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सभा में करीब दो लाख की भीड़ जुटाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने इस बात की वाहवाही तो लूट ली कि उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की आंधी को केवल वही रोक सकते हैं, लेकिन लखनऊ में तीन मंत्रियों को निकाल कर क्या वह अपने खिलाफ उठे विद्रोह को स्थायी रूप से दबाने में कामयाब हो गये हैं ?

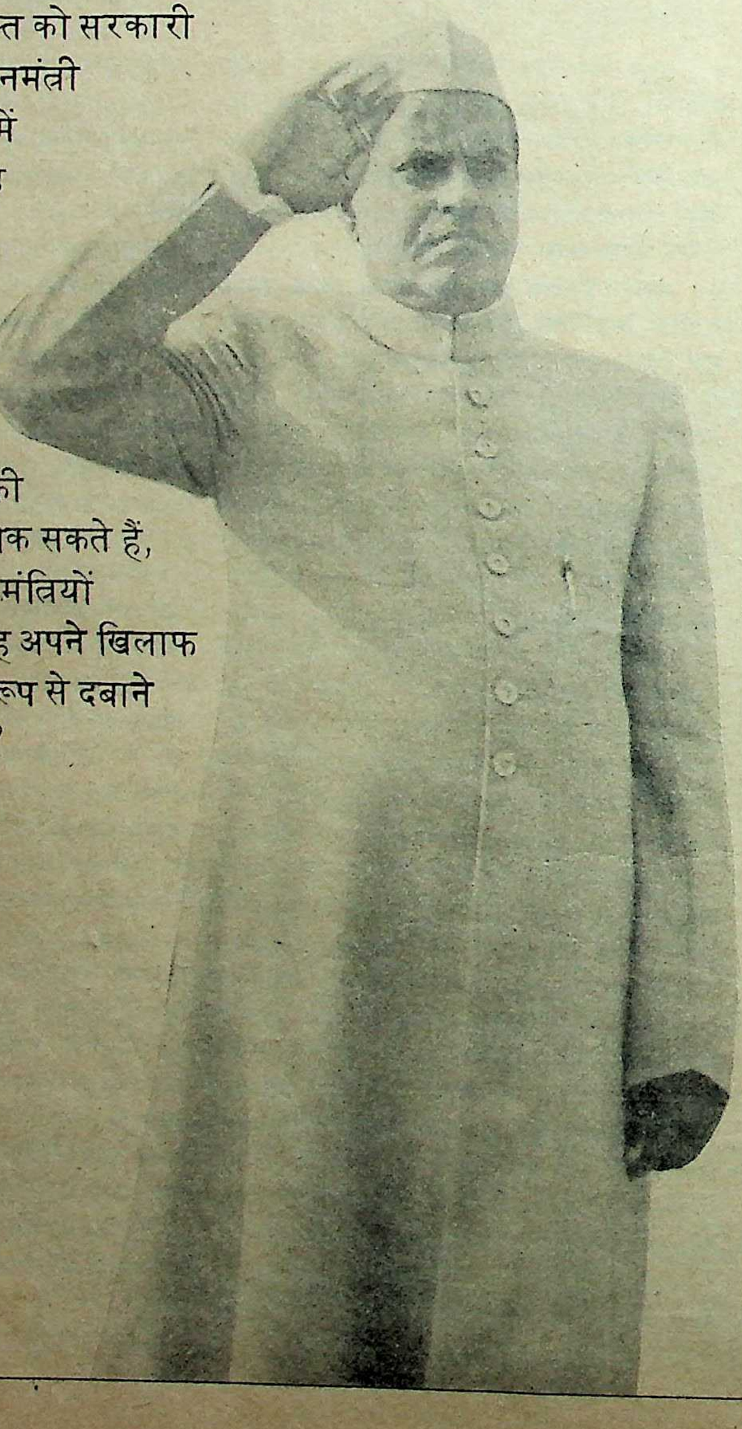

जोड़-तोड़ की राजनीति में माहिर वीर बहादुर सिंह कठिन-से-कठिन घड़ी में भी हवा का रुख अपने पक्ष में कर सकते हैं, यह बात उन्होंने साबित कर दी है। उत्तर प्रदेश में असंतुष्टों की बढ़ती संख्या पर उन्होंने न केवल ब्रेक लगाया है, वरन् बड़ी चालाकी से करीब ५० असंतुष्ट विधायकों को पटाकर अपने पक्ष में कर लिया है। वीर बहादुर कहते हैं, "मुश्किल से १०-१५ विधायक रह गये हैं, मैं इन्हें भी 'ठीक' कर लूंगा। देखता हूं, यू० पी० में कौन असंतुष्ट बचता है ? कुछ लोग 'बहकावे' में आकर राजा के साथ हो गये थे, अब उन्होंने अपनी गलती मान ली है।"

पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश की इंका राजनीति में जो भूचाल उठा था, वह अब थोड़ा शान्त हो गया है। लेकिन यह तूफान आने के पूर्व की शान्ति है। वीर बहादुर मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य संजय सिंह कहते हैं, "उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन निश्चित है, लेकिन इसमें एक डेढ़ महीने का समय जरूर लगेगा। इस बीच वीर बहादुर सिंह अपने को स्थिर बताने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद का विस्तार भी कर सकते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि अगस्त के बाद वीर बहादुर को बोरिया-बिस्तर बांधना पड़ेगा।"

प्रलोभन : वास्तव में १५ जुलाई तक 'वीर बहादुर हटाओ' अभियान पूरे जोर पर था। उस समय तक मुख्यमंत्री, पार्टी-विधायकों को पटाने के लिए उनके क्षेत्र में ५ किलोमीटर पक्की सड़क, एक जूनियर हाई स्कूल और एक डिस्पेन्सरी खोलने का आश्वासन दे रहे थे। यही नहीं, असंतुष्ट इंका विधायकों को 'पटाने' के लिए मुख्यमंत्री और उनके समर्थक जीजान से जुट गये थे। वीर बहादुर के प्रबल समर्थक खान गुफरान जाहिदी जो आवास विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं, असंतुष्टों के बीच घूम-घूम कर कह रहे थे, "मुख्यमंत्री गाजियाबाद में सस्ते दाम पर विधायकों को एक-एक प्लाट देना चाहते हैं। आप लोग प्लाट लीजिए और मुख्यमंत्री में आस्था व्यक्त करने का लिखित बयान दीजिए।" जो विधायक इन सब प्रलोभनों में नहीं आ रहा था, उसे वीर बहादुर समर्थक धमकी दे रहे थे, "अगर मुख्यमंत्री का विरोध किया तो राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दिया जायेगा।"

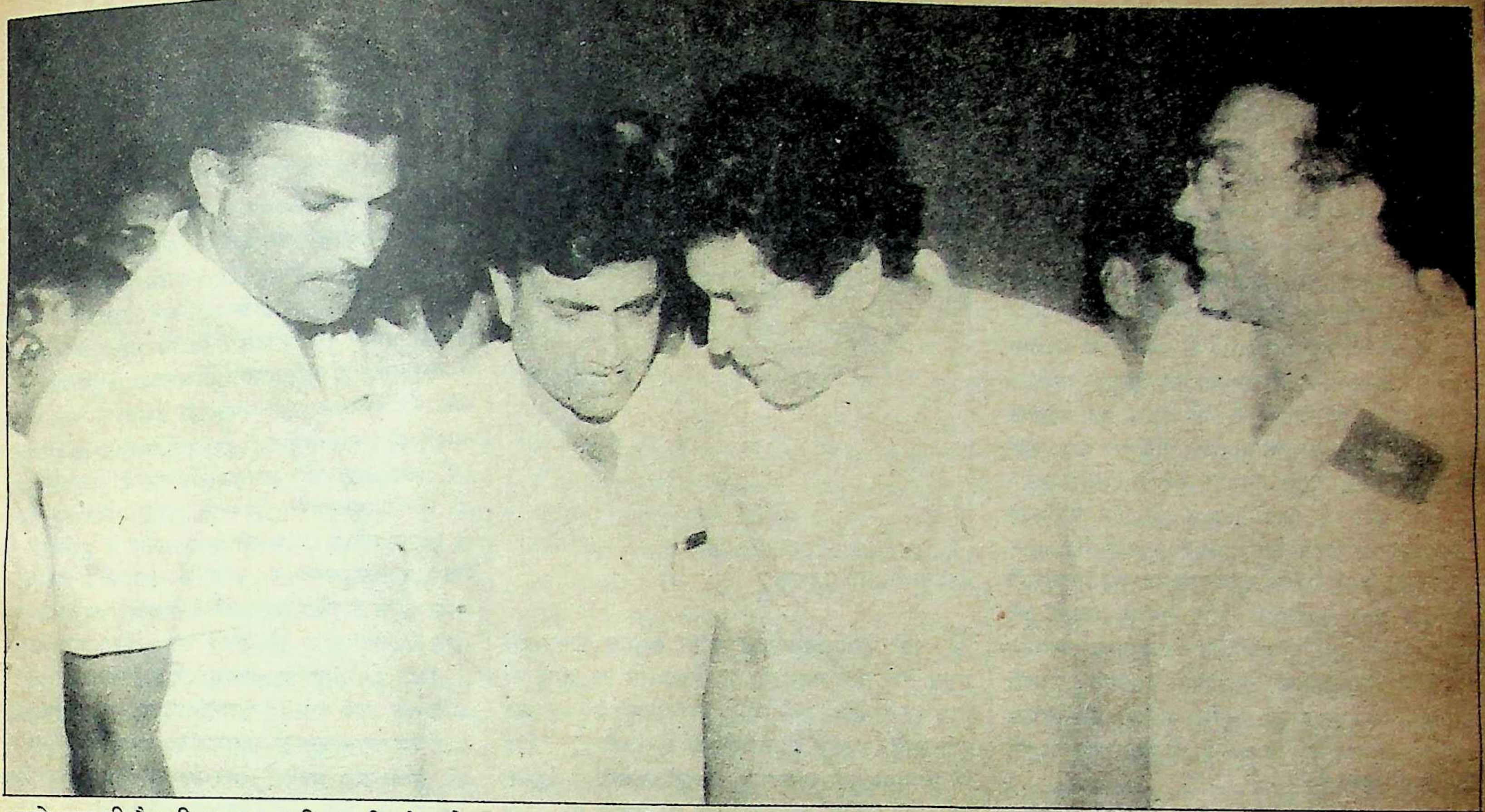

अगले वार की तैयारी : जफर अली नकवी और मोहम्मद असलम खां के साथ राजेश पायलट

लेकिन १५ जुलाई की रात इंका राजनीति ने जो करवट ली, उसका उत्तर प्रदेश के असंतुष्टों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उस रात इंका हाईकमान ने अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां और विद्याचरण शुक्ल को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी। वीर बहादुर उस रात दिल्ली में ही थे। इन तीनों के निष्कासन का विरोध करते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अगले दिन पार्टी के साथ-साथ राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के अपने निर्णय से हाईकमान को अवगत करा दिया। इसकी उत्तर प्रदेश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। १७ जुलाई को उत्तर प्रदेश इंका के २३ असंतुष्ट विधायकों ने एक बयान जारी कर अरुण, आरिफ और शुक्ल के पार्टी से निष्कासन को दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण कदम बताया। इधर लखनऊ में असंतुष्टों की गतिविधियां तेज हो रही थीं, उधर वीर बहादुर सिंह दिल्ली में बैठे असंतुष्टों से निपटने की रणनीति बना रहे थे।

नकवी-सिंह के इस्तीफे : अगले दिन यानी १८ जुलाई की सुबह जब वीर बहादुर सिंह दिल्ली से लौटे, तो काफी खुश थे। ऐसा लग रहा था, जैसे दिल्ली दरबार से उन्हें नया जोश-खरोश मिला है। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने घोषणा की, "मैं अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी मंत्री अनुशासित नहीं रहेगा, उसे निकाल बाहर करूंगा। पार्टी-विरोधी गतिविधियों में लगे विधायकों के साथ सख्ती से निपटूंगा।" वीर बहादुर की इस चेतावनी के बाद ही असंतुष्टों में खलबली मच गयी। उसी शाम सहकारिता राज्यमंत्री सुरेन्द्र सिंह के आवास पर असंतुष्ट विधायकों की एक बैठक में वीर बहादुर के विरुद्ध अगली रणनीति तय की गयी।

इस बैठक की सूचना जब वीर बहादुर सिंह को मिली, तो उन्होंने अपने विश्वासपात्र मंत्री गोपीनाथ दीक्षित के जरिए सुरेन्द्र सिंह और जफर अली नकवी से इस्तीफे तलब कर लिये और अगली सुबह (१९ जुलाई) वीर बहादुर ने मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठक बुला रखी थी। सुरेन्द्र सिंह और जफर अली नकवी ने वहीं मुख्यमंत्री को अपने-अपने इस्तीफे सौंप दिये।

वीर बहादुर सिंह कह रहे थे कि उन्होंने इन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन इन मंत्रियों ने पत्रकारों को अपने इस्तीफे की प्रतियां बांटकर यह बता दिया था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है, वरन् उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है।

जफर अली नकवी का कहना था, "जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय वीर बहादुर सिंचाई मंत्री थे। राजा साहब के पास वीर बहादुर के भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें थीं। वह वीर बहादुर को हटाना चाहते थे। इसी कारण वीर बहादुर, राजा साहब से नाराज थे। मैं राजा साहब के साथ हूं, वीर बहादुर के भ्रष्टाचार में शरीक नहीं था, इसीलिए वह मुझसे नाराज थे।"

उधर सुरेन्द्र सिंह का कहना था, "मेरे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के बाद वीर बहादुर हटाओ मुहिम में और तेजी आयेगी। राजा के साथ प्रदेश के ४० विधायक और १५ सांसद पूरी तरह से हैं। वे किसी भी समय पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त करीब एक सौ विधायक ऐसे हैं जो मौका पड़ने पर राजा का ही साथ देंगे।"

२० जुलाई का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी गर्म रहा। पूरे दिन वीर बहादुर सिंह, असंतुष्ट विधायकों को समझाने और धमकाने में लगे रहे। इलाहाबाद के राजा-समर्थक विधायकों को पटाने की जिम्मेदारी श्याम सूरत उपाध्याय ने ले रखी थी। विधानसभा की लाबी में वीर बहादुर सिंह असंतुष्टों से पहली बार यह कहते देखे गये, "मुझसे जो भी काम कराना हो करा लीजिए, लेकिन यह बयान दीजिए कि राजा के साथ नहीं हैं।"

उधर श्याम सूरत उपाध्याय ने विश्राम दास, रमाकान्त, भोला सिंह, सतीश जायसवाल, शैलेन्द्र कुमार, पुरुषोत्तम लाल तथा ईश्वर शरण विद्यार्थी को काफी समझाया, अनुनय-विनय की, लेकिन बताया जाता है कि विद्यार्थी को छोड़कर किसी ने उन्हें अहमियत नहीं दी।

इसी बीच इंका के प्रादेशिक अध्यक्ष महावीर प्रसाद ने चेतावनी दी, "पार्टी से निकाले गये लोगों को जो इंकाई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग देगा उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी। उसी शाम वीर बहादुर सिंह पत्रकारों पर खूब बिगड़े। उनका कहना था कि नेतृत्व-परिवर्तन की अफवाहें छापने से सरकार और पार्टी पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने २७ विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त एक बयान भी पत्रकारों को वितरित किया, जिसमें कहा गया था, "हमें वर्तमान नेतृत्व में पूरी आस्था है।"

जब मुख्यमंत्री से एक पत्रकार ने यह पूछा, "२६८ विधायकों में से केवल २७ ने ही हस्ताक्षर क्यों किये?" तो मुख्यमंत्री बोले, "सब एक साथ उपलब्ध नहीं हो सके।"

सुनील शास्त्री का इस्तीफा : उसी शाम एक घटना और घट गयी। ऊर्जामंत्री सुनील शास्त्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर इंका के प्रादेशिक महा-

मंत्री दल सिंगार यादव ने भी राजा के समर्थन में पद त्याग कर दिया। शास्त्री के इस्तीफे की खबर दूरदर्शन और आकाशवाणी ने प्रमुखता से प्रसारित की। यह खबर सुनते ही वीर बहादुर ने बयान जारी किया, "सुनील शास्त्री ने खुद इस्तीफा नहीं दिया है। मेरी संस्तुति पर राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त किया है।" साथ ही उन्होंने तत्काल राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ को एक पत्र लिखकर सुनील शास्त्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री का यह पत्र लेकर एक विशेष संदेशवाहक जब राज्यपाल के पास पहुंचा, तो राज्यपाल ने शास्त्री को बर्खास्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल का कहना था कि इसके पूर्व उन्हें शास्त्री का त्यागपत्र प्राप्त हो चुका है। नियमानुसार बर्खास्त उस मंत्री को किया जाता है जो त्यागपत्र देने से इनकार करे।

राज्यपाल के साफ इनकार कर देने पर उन्हें मनाने के लिए वीर बहादुर ने संसदीय कार्यमंत्री अम्मार रिजवी को भेजा, लेकिन राज्यपाल तब भी तैयार नहीं हुए। इस बीच मुख्यमंत्री द्वारा सुनील शास्त्री की बर्खास्तगी की खबर दूरदर्शन के रात्रि समाचार बुलेटिन में प्रसारित हो चुकी थी। राज्यपाल ने अम्मार रिजवी से कहा, "जब मुख्यमंत्री, सुनील शास्त्री को बर्खास्त करने की घोषणा कर ही चुके हैं, तो फिर अनुमति देने की जल्दी क्या है?"

परेशानहाल वीर बहादुर सिंह ने दिल्ली फोन पर आलाकमान से बात की। रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे दिल्ली से आये फोन के बाद राज्यपाल ने अनुमति दे दी। इस तरह सुनील शास्त्री, मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्त किये जाने की घोषणा के बाद लगभग दो घंटे बाद अधिकृत तौर पर बर्खास्त किये गये।

ऊर्जा विभाग के मंत्री के रूप में खासे 'चर्चित' रहे सुनील शास्त्री इस इस्तीफे के बाद जनता के बीच 'हीरो' बन गये। अब तक जो लोग सुनील शास्त्री पर भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप लगाते थे, वही कहने लगे, "बेटे ने इस्तीफा देकर बाप का रास्ता अपनाया है।"

२१ जुलाई को इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफा प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों की मांग थी कि त्यागपत्र देनेवाले मंत्री, नियमानुसार सदन में अपने इस्तीफे का कारण बतायें। जाहिर है, अगर इन मंत्रियों को वक्तव्य की अनुमति दी जाती, तो वे सदन में वीर बहादुर की ही छीछालेदर करते। इसलिए मुख्यमंत्री ने बड़ी चालाकी से विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ाने संबंधी विधेयक को सदन में पेश करा दिया। इस विधेयक के विरोध में जैसे ही विपक्षी दल के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया, सरकार के इशारे पर विधान सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।

पायलट का दौरा : असंतुष्टों की गतिविधियों का जायजा लेने के लिए २१ जुलाई को दिल्ली दरबार ने केन्द्रीयमंत्री राजेश पायलट को लखनऊ भेजा। इंका के करीब २०० विधायकों ने पायलट से अलग-अलग और छोटे-छोटे समूहों में भेंटकर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में अपने विचार बताये। मुख्यमंत्री के समर्थक और विरोधी दोनों ही उस दिन काफी सक्रिय रहे। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप समर्थक राज्यमंत्री हुकुम सिंह ने पायलट को अपने आवास पर शाम की चाय पर आमंत्रित कर लिया। वीर बहादुर को यह बात बुरी लगी। उन्होंने विधायकों को चेतावनी दी, "कोई भी विधायक इस चाय पार्टी में नहीं जायेगा।" अन्ततः यह पार्टी रद्द हो गयी। पायलट का कहना था, "मैंने स्वयं यह निर्णय लिया था कि चाय पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्योंकि किसी एक पक्ष की पार्टी में नहीं जाना चाहिए।"

आश्वस्त : संजय सिह

लेकिन उसी रात वीर बहादुर के आवास पर आयोजित 'डिनर' में शामिल होने के बाद पायलट, सुनील शास्त्री से बात करने उनके आवास पर गये। रात्रि करीब साढ़े बारह बजे जब पायलट और सुनील शास्त्री के बीच बातचीत हो रही थी, मुख्यमंत्री आवास से आये फोन पर पायलट से कहा गया, "मुख्यमंत्री जी, इसी समय दिल्ली जा रहे हैं। आपको भी साथ जाना है।" बातचीत अधूरी छोड़कर पायलट, वीर बहादुर के साथ सरकारी विमान से आधीरात को दिल्ली चले गये।

यद्यपि अगले दिन सुबह पायलट ने असंतुष्ट विधायकों से बातचीत का समय निर्धारित किया था, किन्तु रात में ही उनका रहस्यमय तरीके से दिल्ली लौट जाना असंतुष्टों को काफी अखरा।

वीर बहादुर सिंह अचानक आधीरात को पायलट के साथ दिल्ली क्यों चले गये? इस बारे में छानबीन करने पर 'माया' को पता चला कि उस दिन (२१ जुलाई) कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला दिल्ली में थे। उन्होंने वहां यह ऐलान कर दिया था, "मैं मेरठ के दंगे में मारे गये अल्पसंख्यकों के परिवारवालों से २२ जुलाई को मिलने जाऊंगा।"

फारूख अब्दुल्ला के मेरठ जाने से वहां के हालात और बिगड़ सकते थे। इसलिए जिला प्रशासन ने उनके मेरठ आने पर प्रतिबंध लगा दिया। मेरठ के जिलाधिकारी ने वीर बहादुर को फोन पर यह सूचना दी, साथ ही आग्रह किया कि फारूख अब्दुल्ला को किसी भी प्रकार राजी किया जाये कि वह अपनी मेरठ-यात्रा रद्द कर दें। यही वजह थी कि आधीरात को गृह राज्यमंत्री सुरेन्द्र सिंह चौहान और राजेश पायलट को साथ लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गये। रात्रि में ही उन्होंने सुरेन्द्र सिंह चौहान को दिल्ली से मेरठ भेजा और किसी तरह फारूख अब्दुल्ला की मेरठ यात्रा रद्द कराने में सफल हुए।

राजा को समर्थन : यद्यपि उत्तर प्रदेश में अभी तक तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, करीब ढाई दर्जन विधायक खुलकर विश्वनाथ प्रताप के समर्थन में आ गये हैं और लगभग एक दर्जन सांसद भी इस लड़ाई में राजा के साथ हैं। किन्तु केवल इतने समर्थन से कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में क्रांति नहीं कर सकता है। राजा भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि विधायकों या सांसदों के बल पर कोई अभियान नहीं चलाया जा सकता है। कोई भी अभियान तभी सफल हो सकता है, जब आम जनता की उसमें भागीदारी हो। यही वजह है कि गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ की सभाओं में राजा को जो अपार जनसमर्थन मिला है, उससे राजा समर्थकों के हौसले बढ़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक राजा की तूती बोल रही है। उत्तर प्रदेश के इंका विधायकों में भगदड़ मचने का एक खास कारण राजा को मिल रहा अपार जनसमर्थन है। जिन कांग्रेसियों ने हरियाणा में देवीलाल की आंधी के सामने अपने बड़े-बड़े महारथियों को उखड़ते देखा है, उन्हें अब यह महसूस होने लगा है कि उत्तर प्रदेश में राजा की आंधी चल चुकी है और वह किसी को अपने पैर जमाने नहीं देगी। अपने भविष्य की चिन्ता के कारण इंका विधायक कभी भी वीर बहादुर की घेराबंदी तोड़कर भाग सकते हैं।

इस चुनौती को देखते हुए एक बार तो दिल्ली दरबार ने वीर बहादुर को बदलने का मन बना लिया था। मगर फिर उसे दिखायी दिया कि एक राज्य में नेता बदलने से दूसरे आधा दर्जन राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव पैदा हो जायेगा। अभी किसी भी राज्य में इंका के पास ऐसा नेता नहीं है जो राजा की आंधी को कुछ महीनों के लिए रोक सके। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई नेता नहीं है।

एक बात और है, जिस राज्य में हर विधायक अपने आपको नेता मानता हो, वहां वीर बहादुर सिंह की डराने-धमकानेवाली घुड़कियां काम नहीं आ सकतीं। ये घुड़कियां तो विधायकों को भड़का ही सकती हैं। वीर बहादुर सिंह ने जिस तरह जफर अली नकवी, सुरेन्द्र सिंह और सुनील शास्त्री का इस्तीफा लिया है। उससे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें लोकतंत्रीय तौर-तरीकों का ज्ञान है। उन्हें और हाईकमान को अभी भी यह गलतफहमी है कि राजीव गांधी का जादुई असर पूरे प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजा का कुछ वैसा ही मान-सम्मान नजर आने लगा है, जैसा आन्ध्र में रामाराव और हरियाणा में देवी लाल का है। लेकिन इस सबके जवाब में वीर बहादुर सिंह कहते हैं, "यू०पी० में राजा का कहीं जोर नहीं है। एक आदमी साथ नहीं है। जो १०-१५ विधायक साथ हैं भी, उन्हें मैं जल्द ही ठीक कर लूंगा। एक बार बस मंत्रिपरिषद का विस्तार कर लूं फिर सब ठंडे पड़ जायेंगे।"

—अजय कुमार और निशीथ जोशी

छाया : राजेंद्र कुमार

सूखे से मरे जनता, भत्ता बढ़े विधायकों का

वीर बहादुर सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को मिलनेवाली सुविधाओं और भत्तों में अनापशनाप वृद्धि कर दी है। क्या यह वृद्धि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर की गयी है या वीर बहादुर सिंह ने अपनी सत्ता पर गहराते संकट के कारण विधायकों को अपने पक्ष में बनाये रखने के लिए यह चारा फेंका है ? सूखे के फलस्वरूप आसन्न अकाल की आशंका से त्रस्त देश के बेहद गरीब प्रदेश के अर्थतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विधायकों को वेतन-भत्ते और सुख-सुविधाएं देने की दौड़ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहना चाहता है। इसी २१ जुलाई को 'कुबेर' एक बार फिर प्रदेश के विधायकों पर मेहरबान हो गये। राज्यविधान मण्डल दल के सदस्यों का वेतन भत्ता ढाई हजार से बढ़ा कर चार हजार पचास रुपए कर दिया गया है। वह भी उस समय जब प्रदेश की १२ करोड़ जनता सूखे की लपेट में कराह रही है। सरकार का तर्क था कि महंगाई बढ़ने से जनप्रतिनिधियों को सामाजिक कार्य करने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अतः उन्हें 'राहत' दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं सूखे और बाढ़ की चिन्ता छोड़कर विधायकों को वायुयान यात्रा की सुविधा भी दे दी गयी है।

इस समय हालात ये हैं कि जहां एक ओर पूरा प्रदेश सूखे की विभीषिका से जूझ रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों (विधायकों) में हरियाली छायी हुई है। २१ जुलाई को विधानसभा में सूखे पर चर्चा होनी थी। प्रदेश मंत्रिमंडल से हटने वाले तीन मंत्रियों को बयान देने थे। चार दर्जन से अधिक विभागों व उपविभागों के बजट पारित होने थे। इन सब कार्यों को गैर महत्वपूर्ण समझकर सदन में विधायकों की सुख-सुविधाओं से संबंधित एक संशोधन विधेयक पेश किया गया। जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत विधानमंडल दल के सदस्यों का वेतन भत्ता २५०० रुपए प्रतिमाह से बढ़कर ४०५० रुपए हो गया। इतना ही नहीं, ये जनप्रतिनिधि अब २५ हजार के स्थान पर ३५ हजार रुपए के मुफ्त रेलवे कूपन पाने के हकदार हो गये हैं। अगर कोई विधायक रेल के स्थान पर हवाई जहाज से जाना-आना चाहे, तो वह रेलवे कूपन के बजाय उतने ही मूल्य के 'एयर टिकट' निशुल्क प्राप्त कर सकता है। गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाले इन विधायकों की सुविधा इस हद तक बढ़ाने से राज्य सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष एक करोड़ ४२ लाख, ११ हजार रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ गया है।

आखिरकार जनप्रतिनिधियों को ये सुख-सुविधाएं किस आधार पर दी जाती हैं ? हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता द्वारा पांच वर्ष के लिए चुनकर भेजे गये जनप्रतिनिधि को हर सम्भव सुविधाएं देने का प्रावधान है, ताकि ये जनप्रतिनिधि विधानसभा परिसर, निर्वाचन क्षेत्र और देश में लोकतांत्रिक परम्पराओं को जीवित रखने के लिए कठोरतम संघर्ष करने में सक्षम रहें। यदि १९५२ से विधायकों की परिलब्धियों पर एक नजर डाली जाये, तो स्पष्ट हो जायेगा कि जनता के प्रतिनिधि कहलानेवाले ये विधायक वास्तव में, 'आधुनिक महाराजा' बन चुके हैं।

सुविधाएं-तब और अब : वर्ष १९५२ में विधायकों का मासिक वेतन २०० रुपए था। इसके अतिरिक्त बैठक के दिनों में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के विधायक क्रमशः दस व १५ रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी थे। बैठक में शामिल होने के लिए सिर्फ एक ओर का प्रथम श्रेणी का डेढ़ रेल टिकट मिलता था। बस में यात्रा करने पर प्रथम पचास मील तक पचास पैसे, प्रतिमील, अगले १०० मील तक ३६ पैसे प्रतिमील और शेष दूरी का २५ पैसे प्रतिमील सड़क भत्ते के रूप में प्राप्त होता था। विधानसभा एवं विधान-परिषद की बैठक में चार दिन से अधिक का अवकाश होने की स्थिति में ही यात्रा भत्ता देय था। इससे कम अवकाश पर दैनिक भत्ता मुख्य आवास (लखनऊ) में होने पर ही मिलता था। यदि विधायक घर जाता तो दैनिक भत्ते और यात्रा में जो कम होता वही दिया जाता था।

प्रदेश के विधायकों की परिलब्धियों में वृद्धि की शुरुआत फरवरी, १९५६ से हुई। उस समय विधायकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही रेल-यात्रा दुगुना कर दिया गया। इसी के साथ विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान दस दिनों से कम समय के लिए बाहर जाने और लौटने का प्रथम श्रेणी का किराया देने की सुविधा प्रारंभ की गयी। किन्तु यहां भी प्रावधान था कि यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अप्रैल, १९५७ में यह सुविधा समाप्त कर दी गयी।

फरवरी, १९५६ के पूर्व लखनऊ स्थित विधायक निवास में रहने पर एक कमरे का किराया ४५ रुपए प्रतिमाह था। इसमें संशोधन कर दो कमरोंवाले आवास का वार्षिक किराया १२५ रुपए (९.५० रुपए प्रतिमाह) निर्धारित किया गया। इसी वर्ष विधायकों को बिजली पानी सुविधा सहित किराया मुक्त आवास देने का प्रावधान हो गया। अप्रैल १९५७ से विधायक ३७ रुपए ५० पैसे प्रतिमाह आवास प्रतिकर भत्ते के अधिकारी हो गये। सन १९६० से ६९ के बीच विधायकों को और भी अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं। वर्ष १९६३ में सुसज्जित आवास पानेवाले विधायक को ३५ रुपए तथा आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में ७५ रुपए प्रतिकर भत्ता मिलने लगा।

१ अप्रैल, १९६४ को विधायकों का वेतन २०० से बढ़कर ३०० रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। साथ ही विधायक प्रथम श्रेणी में ढाई हजार किलोमीटर की रेलयात्रा के कूपन पाने का अधिकारी हो गया। इस कूपन पर सिर्फ विधायक ही उत्तर प्रदेश की सीमा में ही सफर कर सकता था। बैठक में भाग लेने के लिए प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा के किराये के बराबर की राशि भी विधायकों को मिलने लगी। सड़क भत्ता पूर्ववत रहा। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों का दैनिक भत्ता एक समान (१५ रुपए प्रतिमाह) हो गया। इसके बाद १९६९ में विधायक को निर्वाचन भत्ता प्रतिमाह १५० रुपए, दैनिक भत्ता २५ रुपए और आवास प्रतिकर भत्ता ९० रुपए मिलने लगा। रेल कूपन के अतिरिक्त विधायक को रोडवेज की बसों में निशुल्क मनचाही यात्रा की सुविधा दे दी गयी।

विधायकों की शिकायत थी कि उन्हें मिलनेवाले रेल कूपन पर्याप्त नहीं होते। वर्ष १९७० से १९७ का काल विधायकों के लिए स्वर्णिम रहा। ५ अप्रैल, १९७३ को सुविधा दी गयी कि विधायक एक वर्ष में १० हजार किलोमीटर रेलयात्रा देश भर में कहीं रेल कूपन के जरिये कर सकते हैं। दो वर्ष बाद १५ अगस्त १९७५ से विधायकों को दैनिक भत्ते के स्थान पर ५५ रुपए प्रतिमाह समेकित भत्ते के रूप में प्राप्त होने लगा।

अंगरक्षकों का बढ़ता शौक

यदि उत्तर-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को मिले अंगरक्षकों को ध्यान में रखकर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लिया जाये, तो कानून व्यवस्था का ढांचा चरमराता नजर आयेगा। शायद इसी कारण प्रदेश के ८५ सांसदों में से ७३ ने शैडो ले रखे हैं। ४२५ वर्तमान विधायकों में १९८ विधायक अंगरक्षकों के सहारे हैं। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सांसदों और विधायकों को दिये गये अंगरक्षकों को गिना जाये, तो कुल ६३५ लोगों के पास ६३८ अंगरक्षक हैं। इनमें १७८ ऐसे लोगों को अंगरक्षक प्राप्त हैं जो गैरसरकारी हैं। इन अंगरक्षकों पर सरकार को प्रतिवर्ष १० लाख, ८१ हजार ७५४ रुपए खर्च करना पड़ रहा है।

इसमें शर्त यह थी की सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने की अवस्था में १५ रुपए प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी। इसी के साथ ही महिला विधायकों को अपने एक सहवर्ती के लिए रेल कूपन प्रयोग करने की छूट दे दी गयी। पुरुष विधायक को भी सत्र में दो बार अपने सहवर्ती को ट्रेन में निशुल्क लाने का अधिकार प्रदान किया गया। विधायक के परिवारजनों को रेल कूपन पर यात्रा की सुविधा के साथ ही आवास प्रतिकर भत्ता १५० रुपए प्रतिमाह कर दिया गया।

विधायकों के भत्ते में पहली बार हुई कटौती से १९७६ में समेकित भत्ता ५५० रुपए से घटकर ३५० रुपए हो गया। सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने पर होने वाली कटौती १० रुपए प्रतिदिन हो गयी। प्रथम श्रेणी के निशुल्क रेल कूपन की सीमा पन्द्रह हजार किलोमीटर कर दी गयी। प्रत्येक सत्र में भाग लेने के लिए माह में दो बार प्रथम श्रेणी की निशुल्क यात्रा और १५ रुपए दैनिक भत्ता पुनः शुरू हो गया।

सरकार की नजर में विधायकों की परिलब्धियां कम थीं। अतः नवम्बर, १९७६ में पुनः संशोधन हुआ जो जनवरी, १९७७ से लागू हुआ। समेकित भत्ता समाप्त कर निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ५०० रुपए और वेतन भी ५०० रुपए प्रतिमाह निश्चित किया गया। साथ ही पांच वर्ष तक विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य रहनेवाले को ३०० रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन देने की व्यवस्था की गयी। पांच वर्ष से अधिक समय तक रहनेवाले को ३५० से ५०० रुपए तक की पेंशन स्वीकृत की गयी। १५ अगस्त, १९४७ से विधानमंडल दल के सदस्य रह चुके लोगों को भी इस प्रावधान में शामिल कर लिया गया।

विधायकों को निशुल्क टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के साथ ४ अप्रैल, १९७९ को दैनिक भत्ता दुगुना (३० रुपए प्रतिमाह) कर दिया गया। अप्रैल, १९८० से जुलाई, १९८७ के बीच तो भाग्य एवं लक्ष्मी दोनों विधायकों पर बहुत मेहरबान रहीं। चूंकि प्रथम श्रेणी के कूपे में जनप्रतिनिधियों को काफी गर्मी लगती थी। इसलिए वर्ष १९८० में व्यवस्था की गयी कि जो सदस्य वातानुकूलित (द्वितीय श्रेणी) के डिब्बे में सफर करना चाहे, तो वह बिना अतिरिक्त शुल्क दिये सफर कर सकता है।

इसी दौरान पांच वर्षों से कुछ समय तक विधायक रहे लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इन विधायकों का तर्क था कि चूंकि वर्ष १९५७ से १९६२ की विधानसभा अपना पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के मात्र २५ दिन पूर्व ही भंग की गयी थी। इसलिए उस समय के सदस्य पांच वर्ष का काल पूरा नहीं कर सके हैं। फलस्वरूप उन्हें पेंशन पाने का अधिकारी नहीं माना जा रहा है। अंततः १ जनवरी, १९८० को एक संशोधन के जरिये इस काल के सभी विधायकों को पेंशन का अधिकारी बना दिया गया।

अब विधायकों को यह शिकायत थी कि उनका दैनिक भत्ता इतना कम है कि शाम होते-होते जेब खाली हो जाती है। (भले ही उनका जेब खर्च, क्षेत्र से अपने काम के लिए आनेवाले वहन करते हैं) सरकार ने १४ अप्रैल, १९८१ को दैनिक भत्ता बढ़ाकर ४० रुपए कर दिया। इसी के साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ५०० रुपए मासिक से बढ़कर १००० रुपए कर दिया गया। अप्रैल, १९८४ में पुनः भत्ते की भारी वृद्धि हुई। दैनिक भत्ता ४० से बढ़कर ६० रुपए प्रतिदिन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता १२५० रुपए मासिक हो गया। पेंशन की न्यूनतम सीमा ५०० व अधिकतम ७५० कर दी गयी।

प्रदेश की आठवीं विधानसभा (वर्ष १९८० से १९८५ के अवधि की) पांच वर्ष पूर्ण होने के तीन माह पूर्व विघटित कर दी गयी थी। इस सत्र के विधायकों को पेंशन से लाभान्वित करने के लिए पेंशन अधिनियम में संशोधन हुआ और ये विधायक १० मार्च, १९८५ से पेंशन पाने के अधिकारी बन गये। वर्ष १९८६ में निर्वाचन भत्ता १६०० रुपए मासिक और एक वर्ष में २५ हजार रुपए मूल्य तक की निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा विधायकों को दी गयी। यात्रा के दौरान विधायकों को अपने परिवार के सदस्यों को साथ रखने का अधिकार भी मिल गया।

विधायक को अपना मकान बनवाने या आवास क्रय करने के लिए एक लाख रुपए ऋण के रूप में दिये जाने की भी व्यवस्था कर दी गयी। राज्य सरकार के अस्पतालों से निशुल्क चिकित्सा सुविधा के साथ बाह्य

एक विधायक पर खर्च : एक लाख रुपए

वर्ष	दैनिक भत्ता	वेतन प्रतिमाह	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्रतिमाह	चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह	यात्राव्यय	अन्य भत्ते
१९५२ से १९५९ के मध्य,	१० रु० (मैदानी क्षेत्र) १५ रु० (पर्वतीय क्षेत्र)	२०० रु०		——	सत्र की बैठक के दौरान आने जाने के लिए प्रथम श्रेणी का कुल डेढ़ रेल टिकट	—
१९६० से १९६९ के मध्य	२५ रुपए	३०० रुपए	१५० रु०	——	प्रथम श्रेणी में ढाई हजार कि० मी० की रेल यात्रा।	९० रु० आवास प्रतिकर भत्ता। प्रदेश भर में मनचाही बस यात्रा मुफ्त।
१९७० से १९७९ के मध्य	३० रु०	५०० रु०	५०० रु०	——	प्रथम श्रेणी में १५ हजार कि० मी० की रेल यात्रा/सहवर्ती को भी रेल यात्रा छूट।	आवास, प्रतिकर भत्ता १५० रु० अधिकतम ५०० रु० की पेंशन व्यवस्था।
१९८० से १९८६	६० रु०	५०० रु०	१६०० रु०	४०० रु०	२५ हजार रु० मूल्य के रेल कूपन, वातानुकूल (द्वितीय श्रेणी) में यात्रा, सुविधा।	न्यूनतम आजीवन पेंशन ७५० रु० तथा अधिकतम १५५० रु० प्रति माह, मकान क्रय करने का ऋण की सीमा एक लाख
जुलाई ८७ से	८५ रु०	८०० रु०	२६०० रु०	६०० रु०	३५ हजार रु० मूल्य के रेल अथवा वायुयान टिकट की सुविधा।	—

वर्तमान में एक विधायक पर औसत वार्षिक व्यय एक लाख रुपए बैठता है। इस व्यय में निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन, अंगरक्षक तथा समितियों की बैठक में शामिल होने के लिए मिलनेवाली राशि शामिल नहीं है।

मंत्रियों का जेब खर्च

जेब खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के ४४ सदस्यों ने १, अप्रैल, १९८५ से ३१ मार्च, १९८६ तक जो जेब खर्च लिया, उसमें सर्वाधिक जेब खर्च लेनेवाले परिवहन मंत्री संजय सिंह थे। तत्कालीन नियोजन मंत्री स्वर्गीय जयराम वर्मा का जेब खर्च सबसे कम अर्थात १ हजार, ३६४ रुपए था। प्रस्तुत है, विवरण :

नाम	पद	जेब खर्च
नारायण दत्त तिवारी	मुख्यमंत्री (तत्कालीन)	१८,८३८.७०
वीर बहादुर सिंह	सिंचाई मंत्री (तत्कालीन)	१७,७५०.००
	(अब मुख्यमंत्री)	७,२००.००
		२४,९५०.००
लोकपति त्रिपाठी	स्वास्थ्य मंत्री	३७,७५०.००
वासुदेव सिंह (अब स्वर्गीय)	खाद्य तथा रसद मंत्री	३,१३०.००
बलदेव सिंह आर्य,	राजस्व मंत्री	१०,९३७.००
सईदुल हसन	श्रम मंत्री	१४,४८७.००
नरेन्द्र सिंह	कृषि मंत्री	४७,०५१.००
अजीत प्रताप सिंह	आबकारी मंत्री (तत्कालीन)	३,८६५.००
स्वरूप कुमारी बक्शी	हरिजन एंव समाज कल्याण	४४,५५०.००
सुनील शास्त्री	उर्जा मंत्री (तत्कालीन)	१८,४६२.१०
संजय सिंह	परिवहन मंत्री	१,१८,३००.००
राम रतन सिंह	संसदीय कार्यमंत्री (तत्कालीन)	१०,१५८.००
गोपीनाथ दीक्षित (तत्कालीनउद्योगमंत्री)	अब गृहमंत्री	१३,३९७.१५
श्याम सूरत उपाध्याय	ग्राम विकास मंत्री	५९,६००.७५
बेनी बाई	पशुधन मंत्री (तत्कालीन)	१४,२३५.००
अरुण कुमार सिंह	सहकारिता मंत्री	४५,५००.००
रघुबीर सिंह यादव	कारागार मंत्री (तत्कालीन)	२३,२४७.००
सैय्यद शिब्ते रजी	शिक्षा मंत्री	२९,६८४.००
जय राम वर्मा (अब स्वर्गीय)	नियोजन मंत्री	१,३६४.६०
राज्य मंत्री		
गुलाब सिंह	पर्वतीय विकास मंत्री (तत्कालीन)	१५,०५०.००
प्रवीण कुमार शर्मा	सा०नि० विभाग	१२,०५०.००
शिव बालक पासी	कृषि	२८,६६२.००
जफर अली नकवी	वन (तत्कालीन)	३६,००७.००
सुरेन्द्र सिंह	ग्राम विकास (तत्कालीन)	३०,०३५.७५
ओम प्रकाश रिछारिया	वित्त	४०,४७५.००
दल जीत सिंह	पशुधन (तत्कालीन)	४०,७२५.००
इन्द्रजीत सिंह	हरिजन समाज कल्याण (तत्कालीन)	२८,८९०.००
गौरी शंकर	राजस्व	१३,२७०.००
दीपक कुमार	सहकारिता (तत्कालीन)	३७,२५३.००
श्रीमती पद्मा सेठ	नगर विकास	१३,६००.००
भोला शंकर मौर्य	सिंचाई	११,३७५.००
मन पाल सिंह	खाद्य रसद	२०,७०१.००
मो० सफीकुर्रहमान अंसारी	उद्योग (तत्कालीन)	८,४५५.२५
संकटा प्रसाद शास्त्री	शिक्षा	१४,२६०.००
श्रीमती सुखदा मिश्रा	उर्जा (तत्कालीन)	१०,५७०.००
सुरेन्द्र सिंह चौहान	न्याय	१४,०६३.००
हुकुम सिंह	संसदीय कार्य	२५,३८०.००
प्रमोद कुमार तिवारी	उर्जा तथा पर्यटन	४,२९०.००
निसार अहमद अंसारी	उद्योग	३,०८०.००
राम औतार दीक्षित	पर्वतीय विकास	४,३७५.००
चेतराम गंगवार	उच्च शिक्षा	४,०८०.००
रामनरेश शुक्ल	सामान्य प्रशासन	४,४९०.००
सीताराम निषाद	सा०नि०वि०	२,४५०.००
कु० सरस्वती अम्माल	श्रम	१,५७०.००

चिकित्सा के नाम पर ४०० रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाने लगा। विधायक का परिवार भी निशुल्क चिकित्सा का अधिकारी हो गया।

विधायकों की आजीवन पेंशन न्यूनतम ७५० रु० प्रतिमाह निर्धारित कर दी गयी। पांच वर्ष से अधिक समय तक सदन की सेवा करनेवाले विधायकों के लिए प्रति अतिरिक्त वर्ष १०० रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन और पेंशन की अधिकतम राशि १५५० रुपए मासिक तय की गयी। साथ ही सरकारी देय बकाया होने की स्थिति में विधायक की पगार भत्ते अथवा पेंशन से ब्याज सहित कटौती का प्रावधान भी कर दिया गया।

जनता से विश्वासघात : अब इसी २१ जुलाई को पारित संशोधन विधेयक से विधायक एयर टिकट लेकर विदेश यात्रा के अधिकारी भी हो गये हैं। विधायकों की वेतन वृद्धि के इस विधेयक को सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह ने 'काला कानून' तथा 'विधायकों को दी जाने वाली खुली रिश्वत' बताया। विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल यादव ने प्रदेश में सूखे की हालात में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने को जनता के साथ विश्वासघात की संज्ञा दी। इस विधेयक के विरोध में विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर अपना धर्म निभाया। अब प्रश्न यह उठता है कि कार्ययंत्रणा समिति, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने का विधेयक सदन में रखने का निर्णय किया गया, तो विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया ?

विधेयक का विरोध करनेवालों से उर्जा राज्य मंत्री का कहना था कि जो इसका विरोध करते हैं, उन्हें बढ़ा हुआ वेतन भत्ता वापस कर देना चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के विधायकों को सांप सूंघ गया। अधिकांश विधायक इस वृद्धि को उचित बताते हुए सरकार की ओर से तर्क देते हैं, 'जब हर क्षेत्र के कर्मचारी वेतन और भत्ते बढ़वा रहे हैं, तो हम (जनता के सेवक) मुफलिसी में दिन क्यों गुजारें ?'

इस प्रकार २०० रुपए मासिक भत्ते और प्रदेश सीमा में निशुल्क यात्रा से शुरू हुई विधायकों की सुविधाएं हवाई यात्रा, निजी मकान पेंशन और बीस गुना भत्ता वृद्धि तक पहुंच गयी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हैं, अब उन्होंने नयी मांग रख दी है कि उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिए जीप खरीदने के उद्देश्य से ब्याजमुक्त ऋण दिया जाये। साथ ही जीप खरीदते समय लगनेवाले सभी टैक्सों को माफ कर दिया जाये। उम्मीद करनी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को निजी जीपें भी मिल जायेंगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि जनप्रतिनिधि अब कोई नयी मांग नहीं रखेंगे ? सुख-सुविधाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक असुविधा के दूर होने पर दूसरी असुविधाएं नजर आने लगती हैं। इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि जनप्रतिनिधियों को अपना कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों को ध्यान में रखकर विधायकों को सुविधा-संपन्न बनाया जाता है, तो यह जनता के धन का दुरुपयोग है, जिसे 'सामूहिक भ्रष्टाचार' की संज्ञा दी जा सकती है।

—निशीथ जोशी और पद्मा श्रीवास्तव

विधानसभाध्यक्ष शंकर राव जगताप

विधानसभा अध्यक्ष पर 'अविश्वास'

दूसरे प्रदेशों में विधानसभाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की घटना आम बन गयी है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास में पहली बार विधानसभाध्यक्ष के विरुद्ध न केवल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बल्कि उन पर कई तरह के आरोप भी लगाये गये। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में कई नयी परंपराएं शुरू हुईं, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध विधानसभाध्यक्ष से था। विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इसके साथ ही कई नये मुद्दे उठ खड़े हुए। क्या विधानसभाध्यक्ष पर लगाये गये आरोप सही हैं? अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने पर प्रतिपक्ष की अब क्या भूमिका होगी?

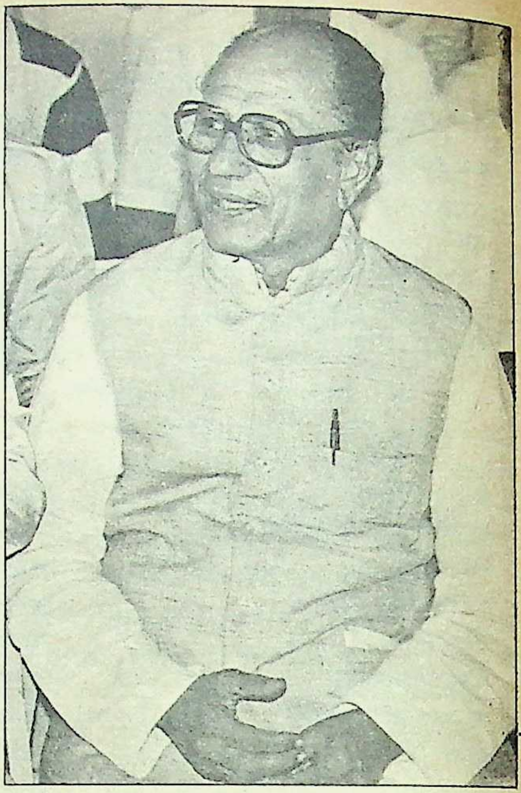

आरोपों का क्या होगा? : शंकर राव जगताप

महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून अधिवेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी—अध्यक्ष शंकर राव जगताप के विरुद्ध प्रतिपक्ष की तरफ से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सदन में उस समय पेश किया गया था, जब वसंत दादा पाटिल, शरद पवार तथा शिवाजी राव पाटील-निलंगेकर के समर्थक तथा असंतुष्ट कांग्रेसीजन मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। एक समय तो राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ दल के बंटने का भी खतरा पैदा हो गया था। प्रतिपक्ष को पूरा विश्वास था कि अनेक खेमों में बंटी कांग्रेस के असंतोष का फायदा वे उठा लेंगे, क्योंकि बहुत से कांग्रेसी भी विधानसभाध्यक्ष से न केवल नाराज थे, बल्कि गाहे-बगाहे वे अपनी नाराजगी प्रकट भी कर दिया करते थे।

श्री जगताप से मुख्यमंत्री चह्वाण तथा भू०पू० मुख्यमंत्री शरद पवार, जो पहले सदन में प्रतिपक्ष के नेता थे, दोनों की कम पटती है, लेकिन इसके बावजूद जहां श्री चह्वाण ने अविश्वास प्रस्ताव को पारित न होने देने की कोशिश की, वहीं श्री पवार ने इस अविश्वास प्रस्ताव-विवाद को दूसरा रूप देने की कोशिश की।

बदलती परंपराएं : पिछले ३० वर्षों में संसदीय परंपराएं बदली हैं तथा चुने गये प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि, वैचारिकता तथा संस्कृति व कार्यकलापों में भी काफी फर्क आ गया है। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं तक नयी-नयी वारदात रोज होती है। इनका असर विशेष सम्मान के पात्र, अध्यक्षों पर भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्षों पर आरोप न लगे हों। उनके विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव भी आये हैं। पहले, लोकसभा अध्यक्ष श्री मावलंकर से लेकर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के साथ तक ऐसा हुआ है। कई राज्य विधानसभा अध्यक्षों के कार्य को लेकर विरोधियों ने टीका-टिप्पणी भी की है।

महाराष्ट्र ने इस मामले में इतिहास बनाया है। संसदीय इतिहास में महाराष्ट्र के नेताओं को अनुभवी तथा संयत व्यवहार के लिए याद किया जाता रहा है। यहां तक कि सरकार के विरुद्ध सभागृह में धरना देने की नौबत तक आयी। फिर भी किसी विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा गया।

पक्षपात का आरोप : विधानसभा के अध्यक्ष शंकर राव जगताप के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भले ही भारी बहुमत से गिर गया हो, परंतु बहस के दौरान श्री जगताप पर सिर्फ पक्षपात के आरोप नहीं लगे। नियमों को ताक पर रखकर मनचाहे फैसले करने, अनचाहे निर्णयों को महीनों तक टालते रहने तथा रिश्तेदारों को फायदा दिलाने जैसे आरोप भी लगाये गये।

श्री जगताप, यशवंत राव चह्वाण के साथ कांग्रेस में वापस आये थे। वह पिछड़े नाई परिवार के हैं, परंतु मेहनत के बल पर बी०ए०, एल-एल०बी० हुए। यशवंत राव और शरद पवार ने राजनीतिक हितों को देखते हुए उन्हें क्रमशः विधायक और विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। सतारा जिले के कुछ अन्य विधायकों की तरह वह उपाध्यक्ष रहते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गये।

श्री जगताप पर विधानसभा में कई बार आरोप लगाया गया कि वह राजनीतिक हित देखकर फैसले लेते हैं। वह शायद पहले व्यक्ति हैं, जो अध्यक्ष होकर भी मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे। सतारा जिले के जावली विधानसभा उपचुनाव में श्री जगताप कांग्रेस का प्रचार करने गये। अन्य राज्यों में भी विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने या चुनाव प्रचार करने से दूर रहते थे, ताकि उन पर पक्षपात का आरोप न लगे। वर्षों पहले राजस्थान विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री निरंजन ने तो सलाह दी थी कि अध्यक्ष के विरुद्ध दलीय उम्मीदवार खड़े नहीं किये जाने चाहिए। ब्रिटेन में इस तरह की परंपरा रही है।

विरोधी सदस्यों का मानना है कि कुछ मंत्रियों और सरकार का बचाव करने में श्री जगताप संतुलन खो बैठते थे। दिसंबर, १९८५ में बंबई में कांग्रेस शताब्दी समारोह हुआ। जनता पार्टी की श्रीमती मृणाल गोरे ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस कर्मचारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने की जिम्मेदारी निभायी। अध्यक्ष की हैसियत से श्री जगताप ने उनके भाषण के इस पूरे हिस्से को कार्यवाही से निकाल दिया।

शेतकरी कामगार पक्ष के दत्ता पाटिल ने ऐसा ही एक और उदाहरण देते हुए बताया कि शिक्षा राज्यमंत्री चंद्रिका केनिया पर श्री जगताप की हमेशा मेहरबानी रही। सुश्री केनिया का युवा जनता के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। इस संबंध में विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव मिलते ही अध्यक्ष ने तुरंत (यानी २२ जून, ८६ को) समिति के पास कार्यवाही के लिए भेजा। इसमें सिर्फ घेराव करनेवालों को आरोपी नहीं बनाया गया था, बल्कि उनके चित्र छापनेवाले अखबारों को भी घसीटा गया।

दूसरी ओर, विशेषाधिकार भंग करने की अनेक सूचनाएं ६ महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष ने विचारार्थ नहीं लीं, फैसला करना तो दूर की बात है।

श्री जगताप पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के राम कापसे ने लगाया। उन्होंने बताया, "विदेश जाते समय श्री जगताप अपने साथ निजी सचिव के बजाय अपने रिश्तेदार को लेकर गये।" अगले दिन श्री कापसे ने उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह गलती से अन्य 'राज्य' के बजाय 'विदेश-दौरा' शब्द बोल गये थे। अतः इस गलती को

दुरुस्त कर लिया जाये।"

आरोपों का खंडन : अगले सप्ताह, श्री जगताप जब लौट कर आये तब कांग्रेस के एक सदस्य ने आरोपों के बारे में जानकारी चाही। मौके का लाभ उठाते हुए श्री जगताप ने कहा, "मुझे खेद है कि चर्चा काफी निचले स्तर पर हुई और मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप लगाये गये। मैं सिर्फ एक बार विदेश गया था। उस समय मैं किसी को भी साथ लेकर नहीं गया था। फिर श्री जगताप ने श्री कापसे को चुनौती दी, "वह 'विदेश-यात्रा' के दौरान रिश्तेदार को साथ ले जाने का आरोप सिद्ध करें, अन्यथा माफी मांगें और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दें।" श्री कापसे ने बारंबार खड़े होकर सफायी देनी चाही, परंतु अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। विरोधी दल के सारे सदस्यों ने एक स्वर में मांग की कि संबंधित सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका दिया जाये, क्योंकि नियमों के अनुसार यह उनका अधिकार है। फिर भी अध्यक्ष ने उनकी एक न सुनी। जब नोंक-झोंक बढ़ गयी तो क्रुद्ध होकर श्री जगताप ने विपक्ष की ओर मुखातिब होकर कहा, "मैं जानता हूं, आप हर मामले में मेरे फैसले को पक्षपातपूर्ण बतायेंगे। अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।"

भाजपा सदस्य श्री कापसे ने बाद में अपना आरोप दोहराते हुए 'माया' से कहा, "मैंने २६ जून, ८७ को विधानसभा के उपाध्यक्ष डा० पद्म सिंह पाटिल को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि 'परराज्य' के बजाय गलती से मैं 'परदेश' बोल गया। रिकार्ड दुरुस्त कर लिया जाये। श्री कापसे ने बताया कि श्री जगताप के साले श्री मोहिले अकसर उनके निजी सचिव की जगह दौरों में जाते हैं। श्री मोहिले पेशे से फोटोग्राफर हैं। वह जाते तो विधानसभा के खर्च पर हैं, परंतु निजी सचिव का काम करने के बजाय बैठकों और समारोहों के फोटो खींचते हैं और उन्हें बेचते हैं। इस तरह, उनके जाने का उद्देश्य सिर्फ धंधा करना होता है। श्री कापसे ने श्री जगताप को चुनौती दी कि वे इस कथन को झूठ साबित करें। अध्यक्ष ने अब तक इस चुनौती का जवाब नहीं दिया है।

विधानसभा के अध्यक्ष शंकर राव जगताप के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भले ही भारी बहुमत से गिर गया हो, परंतु बहस के दौरान श्री जगताप पर सिर्फ पक्षपात के आरोप नहीं लगे। नियमों को ताक पर रखकर मनचाहे फैसले करने, अनचाहे निर्णयों को महीनों तक टालते रहने तथा रिश्तेदारों को फायदा दिलाने जैसे आरोप भी लगाये गये।

साक्षात्कार/विलास देशमुख,

अध्यक्ष पद का मान कायम रहेगा

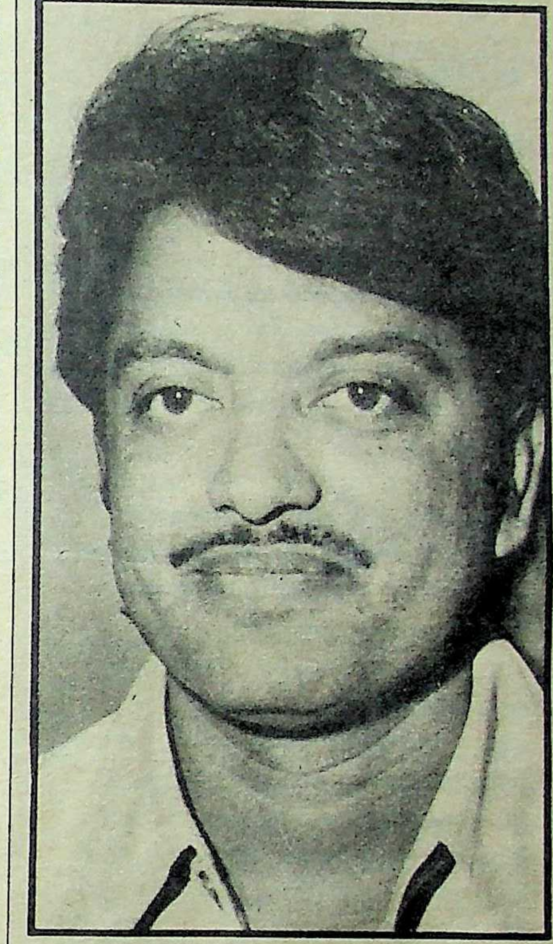

श्री देशमुख की उम्र भले ज्यादा न हो, परंतु मुख्यमंत्री के बाद वह सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं। उनके पास सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, परिवहन, विधानकार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। यह माना जाता है कि श्री चह्वाण के दिल्ली जाने की स्थिति में, वह अगले मुख्यमंत्री होंगे। 'माया' से अध्यक्ष-विवाद पर उनकी बातचीत :

माया : कहा जाता है, कि कांग्रेसी विधायकों ने भी विधानसभा अध्यक्ष शंकर राव जगताप के बारे में शिकायतें की थीं ?

देशमुख : **शिकायतें तो नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ सदस्यों का मत था कि श्री जगताप का विपक्ष की ओर ज्यादा झुकाव रहता है। वह उन्हें ज्यादा अवसर देते हैं।**

माया : **क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री यदि पूरे मन से कोशिश करते, तो विधानसभा में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं आता ?**

देशमुख : **मुख्यमंत्री ने तो अनेक बार विरोधी दलों के नेताओं से बात कर अविश्वास प्रस्ताव पर जोर न देने की सलाह दी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अध्यक्ष श्री जगताप से किसी बात पर नाराजगी या शिकायत हो, तो बातचीत से, मिल-बैठ कर ठीक कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की परंपरा का हवाला दिया, जहां पहले कभी इस तरह का अविश्वास-प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने यहां तक वादा किया कि पहले, भले अध्यक्ष किसी मुख्यमंत्री के कमरे में जाते रहे हों, वह (चह्वाण) इस तरह की गलत परिपाटी नहीं चलने देंगे तथा अध्यक्ष पद का मान कायम रहेगा। उलटे विरोधी दल के नेता यही कहते रहे कि सोचकर बतायेंगे।**

माया : **मतलब विपक्ष ने प्रस्ताव वापस लेने का वादा किया था ?**

देशमुख : **नहीं, यही तो नहीं किया। उनका कहना था, पार्टी से पूछना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं। जब २५ जून को यह रिकार्ड पर आया तब फिर हमारा रुकना या कुछ और समय देना गलत होता ?**

माया : **लेकिन प्रस्ताव रखने के तुरंत बाद चर्चा की मांग की रणनीति क्यों, एक सप्ताह रुक सकते थे, कानूनी प्रावधान है।**

देशमुख : **यह तो अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति (उस समय उपाध्यक्ष) का निर्णय था।**

माया : **कांग्रेस विधायकों तथा मंत्री के रूप में आपकी सहमति के बाद उन्होंने 'रूलिंग' दी।**

देशमुख : **संसद में भी ऐसा होता है। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास पर तुरंत बहस होती है। नंगी तलवार लटकाये रखने से क्या फायदा ?**

माया : **लेकिन उस दिन शंकरराव जगताप भी बंबई में नहीं थे कि खुद के विरुद्ध शिकायतें सुन सकते।**

देशमुख : **प्रोसीडिंग पढ़ लेंगे।**

माया : **एक बात और। उस दिन शरद पवार को यह सलाह देने की क्या जरूरत पड़ गयी कि लड़ाई सरकार से लड़ो ?**

देशमुख : **(हंसकर) मेरे खयाल से वह बता रहे थे कि विपक्ष के नेता की हैसियत से वे क्या करते थे। (रुक कर) जहां तक मैं समझ पाया, उनका कहना था कि दो बार अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव उन्होंने वापस लिया, क्योंकि गुस्से का इजहार नहीं होना चाहिए। उनका मतलब यही रहा होगा कि विपक्ष का काम सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करना है, अध्यक्ष से झगड़ा क्यों किया जाये ?**

माया : **भले ही अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, परंतु श्री जगताप के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों ने फिर रोष का इजहार किया, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में।**

देशमुख : **मेरी जानकारी में तो नहीं है।**

—बंबई ब्यूरो

असलियत क्या है ? : वैसे, ऊपर से पूरा मामला अध्यक्ष के विरुद्ध महज एक अविश्वास प्रस्ताव का लगता है, परंतु इसके अंदर गहरी साजिश लगती है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार भी श्री जगताप के कट्टर दुश्मन बताये जाते हैं। विपक्ष के नेता की हैसियत से, उन्होंने दो बार श्री जगताप के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे, परंतु बाद में मामला रफा-दफा कर दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं आ पाया। एक बार तो विधानसभा के अंदर ही दोनों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई मामला इतना गंभीर हो गया कि श्री जगताप को श्री पवार के और अपने वक्तव्यों को कार्यवाही से निकालना पड़ा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान श्री पवार ने चालाकी बरतते हुए विरोधी दल के सदस्यों को सुझाव दिया कि वह अध्यक्ष से क्यों लड़ते हैं, उनकी असली राजनीतिक लड़ाई तो सामनेवालों से है। उनका इशारा मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण से था, जिनके विरुद्ध पवार का अभियान जारी है।

यों देखा जाये, तो मुख्यमंत्री चह्वाण भी श्री जगताप से खुश नहीं हैं। बताया जाता है कि विधानसभा शुरू होने के पहले—कामकाज के बारे में बातचीत करने विधान परिषद के सभापति जयंत राव तिलक, विधानसभा के अध्यक्ष शंकर राव जगताप और मुख्यमंत्री एक साथ बैठे। श्री तिलक ने कुछ सुझाव दिये, जिन्हें लेकर श्री जगताप ने विरोध में कुछ बातें कहीं। इस कहासुनी से क्षुब्ध मुख्यमंत्री यह कहकर चल दिये कि आप लोग तय करते रहिए, मैं तो जाता हूं। विरोधी नेताओं तक की यह धारणा है कि मुख्यमंत्री ने शुरू में अविश्वास प्रस्ताव न आने देने की आधे मन से कोशिश की। विपक्षी नेताओं ने जब २२ जून, १९८७ को ही प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया तो मुख्यमंत्री ने २५ तारीख को रखने का सुझाव दिया, ताकि वह मौजूद रह सकें। उनकी दिक्कत यह है कि यदि श्री जगताप को निकालने के लिए दबाव डालते हैं तो असंतुष्ट कांग्रेसी प्रचार करेंगे कि (स्व०) यशवंत राव चह्वाण के समर्थकों को कमजोर किया जा रहा है। दूसरे, वह श्री जगताप को मंत्रिमण्डल में लेने के लिए भी उत्सुक नहीं हैं।

इस सारे मामले ने श्री जगताप के मन पर बुरा प्रभाव भी डाला है। इसका उदाहरण उन्होंने तब दिया जब एक प्रस्ताव से सीधा संबंध न होते हुए भी उन्होंने विधानसभा सदस्य केशव राव ढोंडगे के बारे में एक मराठी दैनिक में छपी सालों पुरानी कतरन पढ़कर सुनायी, जिसमें छपा था, "श्री ढोंडगे को मराठी का दो शब्द लिखना नहीं आता, वह चपरासी की नौकरी करने लायक नहीं हैं...।" श्री ढोंडगे महाराष्ट्र विधान सभा के एक वरिष्ठ विधायक हैं, जिनकी जबान से आग बरसती है।

कुछ अखबारों में श्री जगताप के अध्यक्ष-पद से इस्तीफे की खबरें भी छपीं, परंतु इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। यह जरूर है कि अगले अधिवेशन तक कुछ उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की कोप-दृष्टि के कारण जाना पड़ा था। देखें महाराष्ट्र में क्या होता है ?

—बंबई ब्यूरो

छाया : प्रदीप चंद्र

साक्षात्कार/ निहाल अहमद

असली मुद्दा अध्यक्ष की निष्पक्षता और संसदीय परंपराओं का है

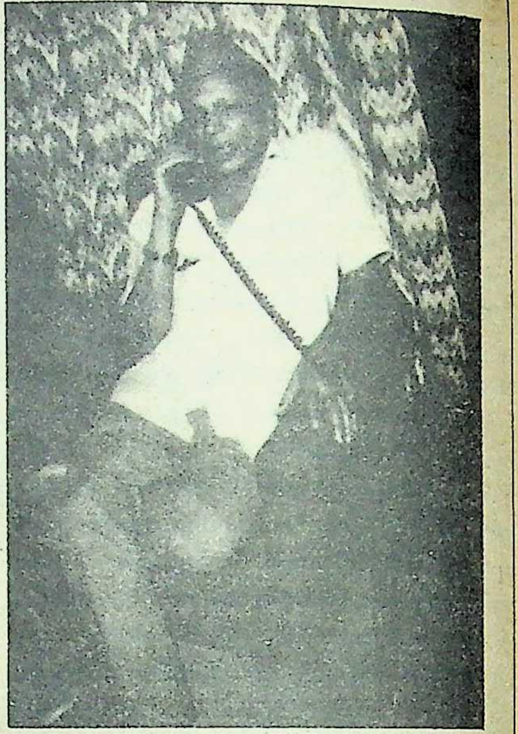

माया : विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखने की क्या जरूरत पड़ गयी ?

निहाल : अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण। हम चाहते थे कि अध्यक्ष पद की गरिमा कायम रहे।

माया : समझौता हो सकता था ? बातचीत से मामला टल सकता था ?

निहाल : देखिए, एक तो मेरी राय है कि मुख्यमंत्री ने आधे मन से कोशिश की। सत्तारूढ़ दल से भी कोई बात छिपी नहीं है। वैसे भी यदि शरद पवार कांग्रेस में न जाते, तो विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा होता।

माया : अध्यक्ष ने मान्य परंपराओं का ऐसा कौन सा उल्लंघन कर दिया ?

निहाल : सारी बातें सामने आ चुकी हैं। एक पुराना किस्सा बतलाता हूं। उस वक्त नाना साहब कुंरे विधानसभा अध्यक्ष थे और मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्रीजी ने किसी काम से कुंरेजी को मिलने के लिए बुलवाया। श्री कुंरे ने जवाब भिजवाया—"अध्यक्ष मिलने नहीं आयेगा। कुंरे आ जायेगा।" मोरारजी भाई को अपनी गलती समझ में आ गयी। वह स्वयं कुंरेजी से मिलने पहुंचे। और हमारे अध्यक्ष महाराज ! मुख्यमंत्री ने बुलाया, तो दौड़कर चले गये। फिर वह कैसे पार्टियों से ऊपर उठ सकेंगे ?

माया : अविश्वास प्रस्ताव आने के पहले बाहर उसकी चर्चा हुई। इसे 'औचित्य-भंग' माना गया ?

निहाल : भाई, असली मुद्दा अध्यक्ष की निष्पक्षता और संसदीय परंपराओं का है। ■

ऐसी है विधानसभा सचिवालय की हालत !

एक अनुभवी तथा योग्य प्रशासक गुणवंत नांदे के विधानसभा सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी देखरेख में आगे बढ़े बी०एम० सुब्रह्मण्यम को सचिव-१ बनाया गया।

महीनों तक श्री सुब्रह्मण्यम विधानसभा की बैठकों में अंदर मौजूद नहीं रहे। कहा जाता है कि अध्यक्ष ने रोका था। श्री जगताप के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अब वह कुछ समय के लिए आते हैं।

विधान सभा कर्मचारियों में इस बात पर रोष है कि उनमें से किसी को पदोन्नत करने के बजाय सी० एम० ढोपरे नाम के एक उपसचिव को बाहर से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया। श्री ढोपरे को कई महीनों से काम-काज में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा उन्हें जानकारियां दी जा रही हैं। बाद में, उन्हें संयुक्त सचिव बनाया जायेगा।

विधानसभा का अलग कर्मचारी-संवर्ग तैयार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। कहते हैं, कुछ बड़ों के अहं के टकराव के कारण मामला खटाई में पड़ा हुआ है।

दो वर्ष से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष को निजी-सचिव नहीं मिल पाया। अब तक उसका स्थान रिक्त है। बतलाते हैं कि श्री जगताप जब उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बने, तो उपाध्यक्ष के कर्मचारी उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए। उस वक्त अध्यक्ष के निजी सचिव अपने विभागों में वापस चले गये।

अप्रैल, ८७ में विधानसभा कर्मचारियों ने वेतन-वृद्धि सहित अनेक मांगों को लेकर विरोधस्वरूप काले फीते बांधकर काम किया, परंतु आश्वासन मिलने के बाद भी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ।

गलियारों में अनेक किस्से सुने जा सकते हैं। किसने लिफ्टमैन पर हाथ उठाया ? किसके ड्राइवर के साथ क्या बर्ताव हुआ ? परंतु, विधानसभा-नियमों तथा परंपराओं के कारण बाहरी दुनिया को इसका पता नहीं लगता। ■

सांप्रदायिकता के बीज किसने बोये ?

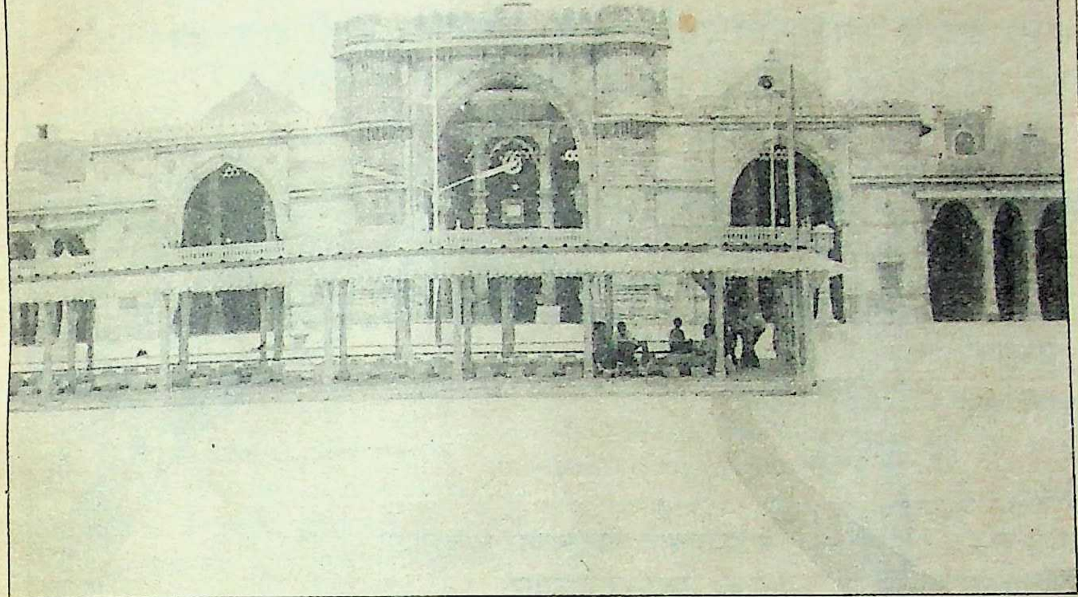

अहमदाबाद की ऐतिहासिक जामा मस्जिद

सांप्रदायिक दंगों की आग में गुजरात आये दिन झुलसता रहता है। दंगों का कारण बनती है, कोई मामूली-सी तात्कालिक घटना—लेकिन यह तो बहाना मात्र होती है। फिरकापरस्ती की स्थायी बारूद बिछानेवाली परिस्थितियां दूसरी हैं। गुजरात में दंगों के स्थायी कारणों की पड़ताल :

गुजरात सांप्रदायिक दंगों का स्थायी केंद्र बन गया है। यदि देखा जाये, तो इसके बीज उत्तरी राज्यों से रोजी-रोटी के लिए आये गरीब हिंदुओं और मुसलमानों ने बोये हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों से आये ये हिंदू और मुसलमान यहां दंगे भड़काने के लिए ही आते हैं। उनकी नीयत साफ है, लेकिन उनके विश्वास और उनके मानसिक रुझान आरामतलब मूल गुजरातियों को रास नहीं आते। सम्भवतः इसी से टकराव-तनाव की स्थितियां बनती हैं और जिसकी परिणति दंगों में होती है।

अपने राज्यों की गरीबी इन बदनसीब मजदूरों को गुजरात में धकेल कर लाती है और यह दरिद्रता ही इन्हें मौलवी का प्रशिक्षण लेने और भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बनने के लिए विवश करती है।

एक समय था, जब गुजराती हिंदुओं और गुजराती मुसलमानों के बीच प्रगाढ़ संबंध थे, जिसका एक मात्र कारण था 'गुजरातीपन'। पर अब बाहरी प्रभाव ने इस अटूट बंधन को ढीला कर दिया है। लेकिन दाऊदी बोहरा और इस्माइली खोजा समुदायों में आज भी गुजराती हिंदुओं के प्रति यह पारंपरिक सद्भाव देखा जा सकता है। यही कारण है कि जब भी कभी दंगे भड़कते हैं, तो ये दोनों समुदाय पसोपेश में पड़ जाते हैं। एक ओर, वे अपने गुजराती हिन्दू भाइयों पर हमला करना मुनासिब नहीं समझते और दूसरी ओर, वे डरते रहते हैं कि कहीं ये हिंदू उन पर हमला न कर दें।

'अगुजरातीकरण' की प्रक्रिया हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में ज्यादा दिखायी पड़ती है। शायद यही कारण है कि गुजरात, उसमें भी खासकर, अहमदाबाद में, अधिसंख्य मौलवी उत्तर के ही हैं। वे धार्मिक मामलों में तो सक्रिय हैं ही, मस्जिदों के ट्रस्टों पर भी वे हावी हैं।

जहां देवबंदी दक्षिणी गुजरात में प्रभावी हैं, वहां अहमदाबाद की मस्जिदें बरेली मौलवियों द्वारा चलायी जाती हैं। देवबंदी ज्यादा रूढ़िवादी वहाबी संप्रदाय के हैं। मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन अशरफी अहमदाबाद जामा मस्जिद के पेश इमाम हैं। इस ऐतिहासिक मस्जिद को अहमदाबाद के संस्थापक सुल्तान अहमदशाह ने शहर के मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए सन् १४२३ में बनवाया था। हर जुमे की नमाज पर इसमें ८००० नमाजी इकट्ठे होते हैं। रमजान और बकरीद के मौकों पर तो इस मस्जिद के बाहरी हिस्सों में असंख्य नमाजी कई कतारों में नमाज अदा करते हैं।

पेश इमाम बड़े सरल स्वभाव के इंसान हैं। वह २४ साल पहले नायब पेश इमाम की हैसियत से जामा मस्जिद में आये थे। मूलतः, वह बिहार में भागलपुर के रहनेवाले हैं। वह 'जामे नजीबिया' मुरादाबाद में दस वर्षों की ट्रेनिंग के बाद अहमदाबाद आये थे। उनको हर महीने ६०० रुपए तनख्वाह तो मिलती ही है, इसके अलावा इन्हें रमजान में भेंट और 'तकरीर' से भी आमदनी हो जाती है।

गुजराती पेश इमाम कम ही हो पाते हैं। इसका कारण मौलाना अशरफी यह मानते हैं कि इस सूबे के मुसलमान रुपया बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जबकि पेश इमामी का काम ज्यादा मेहनत का तो है ही, कम फायदेवाला भी है। वह स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस पेशे को इसलिए चुनते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर गरीब हैं और इस पेशे को विकल्प के रूप में चुनना पसंद करते हैं। यों पेश इमाम के तीन बेटे हैं, लेकिन इनमें से एक ही उनके नक्शेकदम पर चलता है। उसको हाफिज (जिसे कुरान कंठस्थ हो) बनने के लिए इन्होंने बिहार के किसी ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल करा दिया है।

उनसे यह पूछे जाने पर कि कुछ गुजराती मौलवी कोई 'तकरीर' क्यों नहीं करते ? उनका जवाब था कि वैसा करने के लिए और कहने के लिए कुछ तो होना चाहिए। एक अनभिज्ञ आदमी 'तकरीर' कर ही नहीं सकता। इस प्रकार, गुजराती-मूल के मौलवियों की परंपरा समाप्त होती जा रही है। गुजरात में मौलवियों के ट्रेनिंग सेंटरों में भी ज्यादातर छात्र उत्तरी राज्यों के ही

सरल स्वभाव के इंसान : मौलाना अशरफी

हैं। लेकिन यू०पी० वालों का तकरीर का जो तरीका है वह स्थानीय मुसलमानों में अलगाव पैदा करता है यदि मौलवी गुजराती नहीं है, तो वह लोगों को प्रभावि नहीं कर पाता। यही हाल अस्तोदिया क्षेत्र की रान सिपरी मस्जिद का भी है, जिसे सुल्तान मोहम्मद बेगव की बेगम ने बनवाया था। इसका बंदोबस्त छीपा जमा के हाथ में है। यह समुदाय शताब्दियों पहले राजस्था से आया था। इसलिए परंपरानुसार ये राजस्थान मौलवियों को ही अपने यहां जगह देते हैं। मौजू मौलवी उ० प्र० के आजमगढ़ जिले के हैं, जबकि इन पूर्व टोंक के मौलवी थे।

जामा मस्जिद के पेश इमाम की तरह, रा सिपरी मस्जिद के मौलवी मौलाना मोहम्मद सिद्दी साहब भी बेहद शरीफ इंसान हैं। वह बरेलवी संप्र के हैं। उर्दू में इनकी तकरीरें भी शुद्धतावादी ही हो हैं। उनको चिंता है कि गुजराती, इस्लाम का उत

स्वतंत्र भारत के 40 वर्ष

पिछले चार दशकों में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरेक देशवासी के सामने एक ही लक्ष्य है—मिलजुल कर देश को प्रगति की राह पर सबसे आगे ले जाना—

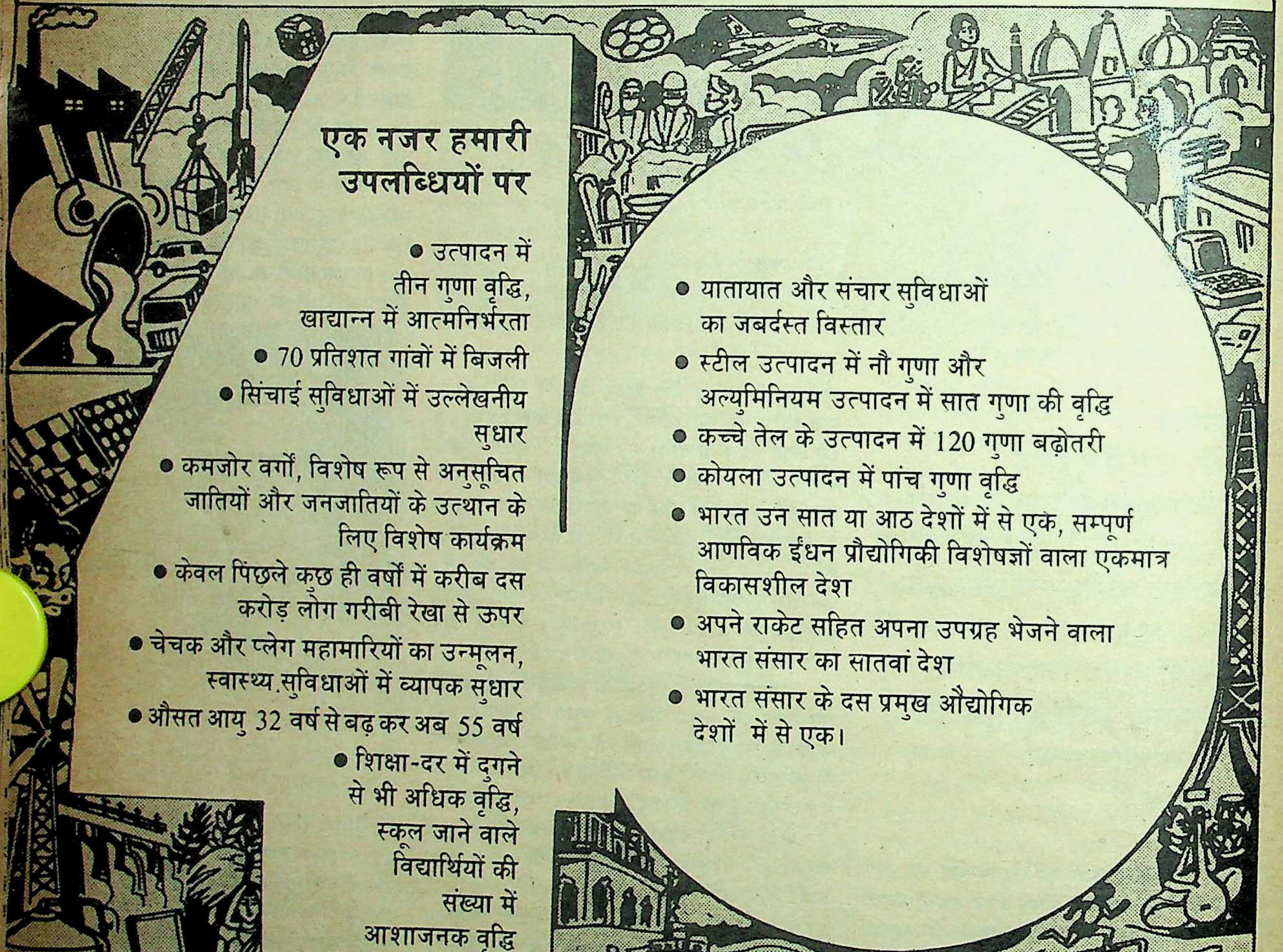

एक नजर हमारी उपलब्धियों पर

- उत्पादन में तीन गुणा वृद्धि, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता
- 70 प्रतिशत गांवों में बिजली
- सिंचाई सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार
- कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम
- केवल पिछले कुछ ही वर्षों में करीब दस करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर
- चेचक और प्लेग महामारियों का उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार
- औसत आयु 32 वर्ष से बढ़ कर अब 55 वर्ष
- शिक्षा-दर में दुगने से भी अधिक वृद्धि, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में आशाजनक वृद्धि
- यातायात और संचार सुविधाओं का जबर्दस्त विस्तार
- स्टील उत्पादन में नौ गुणा और अल्युमिनियम उत्पादन में सात गुणा की वृद्धि
- कच्चे तेल के उत्पादन में 120 गुणा बढ़ोतरी
- कोयला उत्पादन में पांच गुणा वृद्धि
- भारत उन सात या आठ देशों में से एक, सम्पूर्ण आणविक ईंधन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों वाला एकमात्र विकासशील देश
- अपने राकेट सहित अपना उपग्रह भेजने वाला भारत संसार का सातवां देश
- भारत संसार के दस प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक।

इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमने एक बहुत लम्बा रास्ता तय किया है। लेकिन हमें अभी भी महात्मा गांधी का सपना पूरा करना है-हरेक आंख से आंसू पौंछने हैं। वास्तव में, मंजिल अभी और दूर है। लेकिन अपनी इन उपलब्धियों पर हम गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं।

हमें अपनी प्रगति पर गर्व है।

निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते, जितना कि उन्हें करना चाहिए। वह मानते हैं कि गरीब गुजराती मुसलमान भी केवल रुपयों के पीछे हैं। उ०प्र० में धार्मिक पेशे की लोगों की नजर में बड़ी कदर है। इस्लाम गरीबों में पैदा हुआ था, गरीबों के लिए था और वे गरीब ही थे, जिन्होंने इस्लाम को जीवित रखा। बलपूर्वक उन्होंने कहा, "उ०प्र० के मुसलमान अपने उर्दू के ऊंचे ज्ञान तथा सही उच्चारण के कारण धार्मिक कर्तव्यों के प्रति सजग हैं।" लेकिन इनकी अतिशय धार्मिक निष्ठा भी दुराव पैदा करती है।

मुसलमानों का कपलूर-दरियापुर इलाका खूनी दंगों का क्षेत्र है। रखियाल, गोमतीपुर, बापूनगर और अमरायडी ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, जहां के निवासी उत्तरी राज्यों से आये हैं। यहां तक कि अहमदाबाद के शराब के बादशाह अब्दुल लतीफ भी राजस्थान के निवासी हैं। यदि दंगा केवल गुजराती मुसलमानों तक ही सीमित रहे, तो एक-दो दिन से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उत्तरी राज्यों के कुछ तत्वों के मिलते ही दंगा तेज हो जाता है और अगले दंगे का बीज बोकर ही थमता है।

यहां तक कि गुजराती हिंदुओं में भी कुछ पटेलों और कुछ ठाकुरों को छोड़कर सांप्रदायिक दंगों में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता। चूंकि उत्तर के मौलवियों द्वारा मस्जिदों की देखरेख होती है, इसलिए मंदिरों की स्थिति भी उससे भिन्न नहीं है। यदि महंती पुश्तैनी नहीं है, तो गुजरात के मंदिर 'अखाड़ों' द्वारा संचालित होते हैं, जिनके प्रधान कार्यालय हरिद्वार और ऋषिकेश में हैं। साधुओं की सदस्यतावाले ये अखाड़े मंदिरों को संचालित करते हैं और वे भी अपने विशुद्ध धर्मोपदेशों के कारण जाने जाते हैं। उनकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी प्रभावशाली तो है, लेकिन वह पूरी तरह गुजरातियों द्वारा समझी नहीं जाती है। उदाहरण के लिए, वेद मंदिर के प्रधान स्वामी गंगेश्वरानंद, अद्वैत आश्रम मंदिर के स्वामी व्रजलालपुरी, और संन्यास आश्रम मंदिर के स्वामी विश्वदेवानंदजी महराज, सभी उत्तर के ही हैं। ये तीनों विद्वान हैं, लेकिन गुजरातीपन या उदारता की इनमें कमी मानी जाती है।

रायपुर मंदिर के शंभु महराज एकमात्र गुजराती हैं, लेकिन वह प्रायः भीड़ जुटाने वाले ही आदमी हैं। उत्तर भारत के लोग निरंतर मूल गुजरातियों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। कालांतर में जब उनका पूरी तरह से उत्तर भारतीयकरण हो जायेगा, तो दंगा करने की उनकी क्षमता कितनी हो जायेगी, इसका अनुमान ही भयावह है। लेकिन दुर्भाग्य से आसार ऐसे ही हैं। —अरविंद जे० बोसमिया

दंगों की जड़

गुजरात के प्रायः सभी क्षेत्रों में आये-दिन भड़क उठनेवाली सांप्रदायिक हिंसा के मूल कारणों का पता लगाने के लिए हाल में अहमदाबाद के पुलिस अधीक्षक एस०एन० सिन्हा ने नमूने के तौर पर गुजरात के सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित चार नगरों केहरालू (उत्तरी गुजरात), बारडोली (दक्षिणी गुजरात), कंथारिया (बड़ौच जिला) और दमोइज का अध्ययन किया। श्री सिन्हा गुप्तचर विभाग के पुलिस महानिरीक्षक भी रह चुके हैं। इनके अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रायः हर दंगे की शुरुआत बहुत मामूली घटना से होती है, मसलन किसी एक वर्ग की लड़की से दूसरे वर्ग के किसी आदमी द्वारा छेड़छाड़ या परस्पर गाली-गलौज दंगों का तात्कालिक कारण बनते रहे हैं, लेकिन इन्हें सांप्रदायिक दंगों का मूल कारण नहीं कहा जा सकता।

इस अध्ययन के अनुसार सांप्रदायिक दंगों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए हमें सांप्रदायिक विद्वेष को जन्म देनेवाली राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की तह में जाना होगा। ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में आर्थिक कारणों की एक अहम भूमिका रहती है। गुजरात के मुख्य शहरों की आबादी में पहले आमतौर पर दो तरह के लोग थे। एक अमीर और दूसरे गरीब। गरीब तबका अपने जीवन-यापन के लिए अमीर तबके पर आश्रित था। लेकिन आजादी के बाद यह गरीब तबका भी धीरे-धीरे तरक्की करने लगा और अमीरों पर उसका परावलंबन भी कम होने लगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में दोनों वर्ग एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करने लगे।

केहरालू में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती थी। बहरहाल, यहां राजनीतिक नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में है, तो समाज-विरोधी तत्वों की ओट में वहां मुसलमान हावी हैं। कुछ मुसलमानों ने यहां नगर पंचायत के प्रमुख पर इसलिए हमला किया था, क्योंकि उसने एक वर्ग की समाज-विरोधी गतिविधियों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। थाने में इस वारदात की रिपोर्ट लिखायी गयी। प्रेमजी भाई ठक्कर ने दिसंबर, १९८३ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित 'एकात्मता यात्रा' का नेतृत्व किया था। इसे मुसलमानों ने हिंदुओं का अपने ऊपर परोक्ष हमला माना। १६ जनवरी, १९८४ को ठक्कर पर हमला हुआ। बाद में इस घटना के दौरान मुसलमानों ने देसी कट्टे से हिंदुओं पर फायर किये। इस झगड़े में ७ हिंदू और तीन मुसलमानों को चोटें आयीं। फिर ५ मार्च, १९८४ को वहां दंगा भड़का।

बारडोली में तो विभिन्न समुदायों की व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का कारण बनी है। कांग्रेस-इ के भंडारी और उनके भूतपूर्व व्यावसायिक भागीदार अब्दुल हफीज की व्यक्तिगत दुश्मनी ने यहां सांप्रदायिक तनाव फैलाया।

कंथारिया में तो भूपतियों और कृषि श्रमिकों की आपसी तकरार की वजह से सांप्रदायिक तनाव है। यहां भूपति मुसलमान हैं, लेकिन उनके मजदूर हरिजन हैं। शहर में हिंदुओं में हरिजनों की ही संख्या अधिक है। इधर हरिजनों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है और अब वह हर बात के लिए अपने मुस्लिम स्वामियों के मोहताज नहीं रह गये हैं। दोनों वर्गों के बीच एक दूसरे के विरुद्ध भीतर-भीतर ही तनाव बना रहता है। १८ जून, १९८४ को एक हरिजन साइकिल सवार एक मुस्लिम मोपेड सवार से टकरा गया। इस मामूली घटना से वहां दंगा भड़क उठा। मुस्लिम भूपतियों के २०० से अधिक लोगों ने घातक हथियारों से लैस होकर हरिजन बस्ती पर हमला बोल दिया और उनके घर जला दिये। इस हमले में १३ हरिजन घायल हुए और ३ लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ।

दमोइज में तो सांप्रदायिक तनाव सिखों और मुसलमानों के बीच है। भारत-विभाजन के समय पाकिस्तान से आये सिखों को यहां जमाने में स्थानीय मुसलमानों का सहयोग मिला था, लेकिन समय गुजरने के साथ-साथ सिख व्यवसाय में तरक्की करने लगे और आज हालत यह है कि यहां प्रायः हर सिख परिवार जमीन-जायदाद के अलावा एक दो ट्रकों का मालिक भी है। इन नवधनाढ्य सिख-युवकों के उच्छृंखल व्यवहार से मुसलमान खिन्न रहते थे। ११ मार्च, १९८४ को एक मुस्लिम लड़की ने अपने घर के लोगों को एक सिख द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत की। फिर क्या था, मुसलमानों की एक भीड़ हथियारों से लैस होकर सिखों पर टूट पड़ी। एक सिख और एक मुसलमान घायल हो गया। सिखों की एक लाख रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गयी। सिन्हा द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार मुसलमानों की आक्रामक प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण मुस्लिम युवकों की बदली मानसिकता भी है। वे मानते हैं कि उन्हें स्थायी रूप से भारत में ही रहना है, अतः वे भारतीय समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। उनके दिलोदिमाग में यह भरा हुआ है कि वे इस मुल्क के शासक रहे हैं, अतः उनके लिए यही वह 'उचित स्थान' है जो उन्हें भारतीय समाज में मिलना चाहिए। जहां-जहां मुसलमान समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। (जैसे बारडोली में), वहां-वहां हिंदुओं में खिन्नता बढ़ रही है। वे देखते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती समृद्धि का स्रोत तस्करी या अन्य समाज विरोधी गतिविधियां हैं, तो केहरालू के समान वे इनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही की मांग करते हैं। केहरालू में प्रेमजी भाई ठक्कर हिंदुओं के ऐसे नेता माने जाते हैं, जो मुसलमानों के समाज-विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत हैं। एस०एन सिन्हा के अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि हिंदुओं की जवाबी कार्यवाही से मुसलमानों का नेतृत्व भी बड़ी तेजी से पुराने और ठंडे दिमाग वाले बुजुर्गों के हाथों से निकलकर गर्म-मिजाज के युवकों के हाथों में जा रहा है। ये वे युवक हैं, जो हिंसा भड़काने से पहले अंजाम की फिक्र नहीं करते। इन युवकों के पास अवैध धंधों से कमाया काफी धन भी है, जिसकी वजह से ये अपने समुदाय में सरलता से हावी हो जाते हैं और जहां-जहां यह नया नेतृत्व शक्तिशाली हो जाता है, वहां सांप्रदायिक दंगे रोजमर्रा की बातें बन जाते हैं। ■

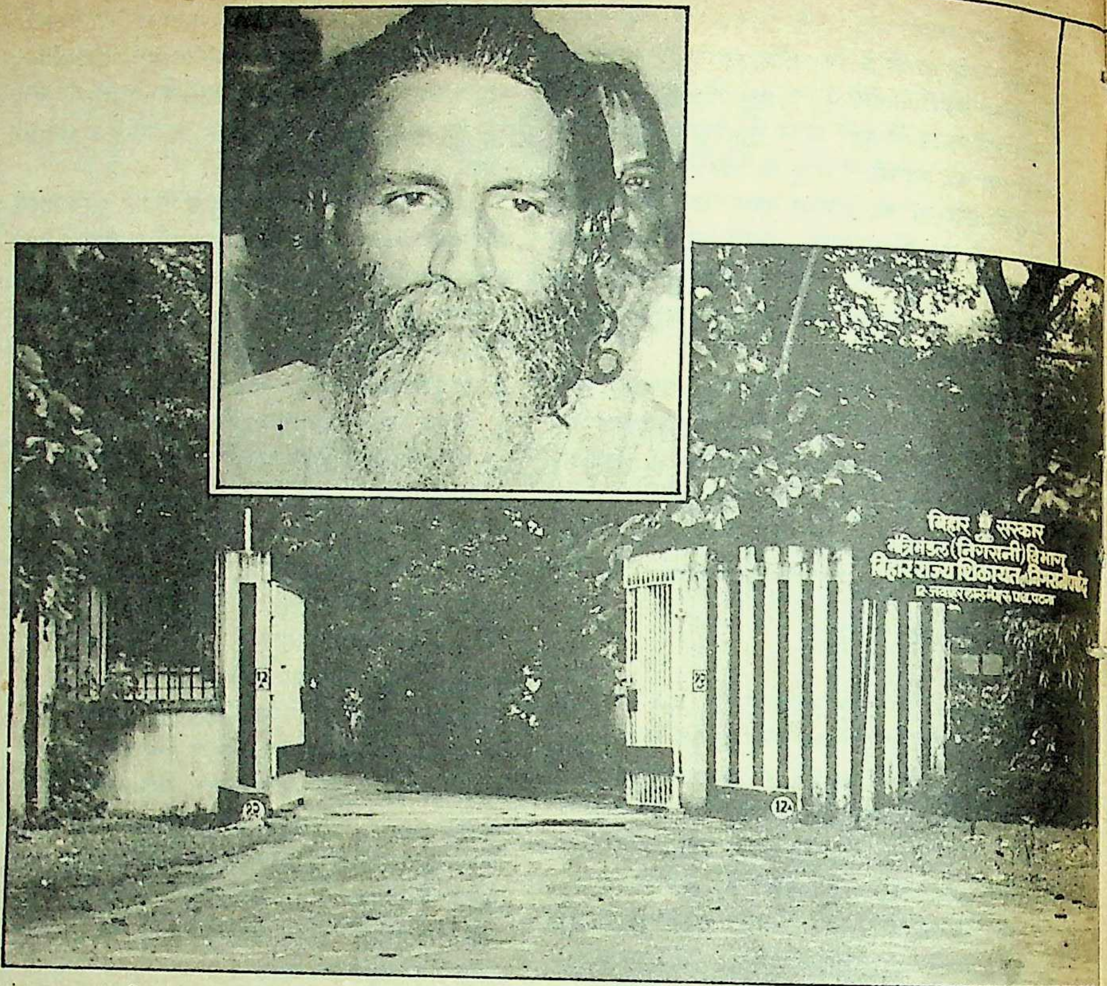
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग
बिहार राज्य शिकायत एवं निगरानी पर्षद
12

संत का राजसी आवास: स्वामी हरिनारायणानंदजी (इनसेट)

स्वामी हरिनारायणानंद

संकट में सरकारी संत

बिहार की राजनीति में तीन दशकों से प्रतिष्ठित सरकारी संत हरिनारायणानंदजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की राजनीतिक ग्रहदशा सुधार रहे हैं, तो बदले में दुबेजी ने उन्हें 'बिहार राज्य शिकायत एवं निगरानी पर्षद्' का उपाध्यक्ष बनाकर उनकी आर्थिक दशा सुधारने का बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन अब यह सरकारी संत और उनका पद दोनों संकट में हैं। न केवल निर्दलीय विधायक राजो सिंह पुराने कारनामों को उजागर करते हुए उनके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके मुकाबले में एक और संत बाबा बलराम भी मंच पर आ गये हैं। क्या दुबे सरकारी संत की रक्षा कर सकेंगे?

बिहार राजनीति में विगत तीन दशक से 'सरकारी संत' के रूप में प्रतिष्ठित स्वामी हरिनारायणानंद की राजनीतिक ग्रहदशा तेजी से बिगड़ती जा रही है। स्वामी पर अनायास उभरे संकट का कारण उनकी स्वजातीय लॉबी ही है, जो मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के दरबार में स्वामी की दुर्गति करने पर तुली हुई है। बेचारे स्वामी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अपनी जाति के प्रति इतना अनुराग रखने के बावजूद उन्हें अपनी ही जाति से विरोध क्यों मिल रहा है। निर्दलीय विधायक व पूर्वराज्यमंत्री राजो सिंह स्वामी की आध्यात्मिक—राजनीति के खिलाफ बिल्कुल सत्तू बांधकर पीछे पड़ गये हैं, इस संकल्प के साथ कि भगवा वस्त्र की राजनीतिक पोल वह खोलकर ही दम लेंगे। राजो सिंह ने स्वामी पर कई संगीन आरोप लगाये हैं कि स्वामी ने तकरीबन २० वर्ष पूर्व एक महंत की हत्या कर दी थी। भोला पासवान शास्त्री उन दिनों जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो मामला रफादफा करवाने की हर संभव कोशिश की गयी थी, पर शास्त्री तैयार नहीं हुए थे, लेकिन बाद में स्वामी ने मामला खत्म करवा ही दिया। राजो सिंह कहते हैं कि १९७३ में भी मैंने विधान सभा में इस स्वामी की ऐसी ही हरकतों का विरोध किया था। अब भी मेरे विरोध का मुद्दा वही है कि संत का बाना पहनकर कोई राजनीतिक भ्रष्टाचार का खेल इस तरह नहीं खेले। राजो का आरोप है कि 'बिहार राज्य शिकायत एवं निगरानी पर्षद्' के उपाध्यक्ष की हैसियत से स्वामी ने तो भ्रष्टाचार का बाजार ही खोल दिया है। राजो कहते हैं कि अभी हाल में अखबारों में स्वामी के हवाले से जब यह खबर छपी कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने कुछ मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो पढ़कर मुझे लगा कि यह स्वामी कितने ओछे और हास्यास्पद करतब कर रहा है। अगर 'निगरानी पर्षद्' के उपाध्यक्ष के नाते उन्होंने ऐसा किया भी तो उसे गोपनीय रखना चाहिए था न कि अखबार में समाचार प्रकाशित करवाना चाहिए था। वह निरंतर इस तरह अपनी सीमा लांघते जा रहे थे। नतीजतन, मुझे लगा अब और चुप नहीं रहना चाहिए।

संत के पीछे विधायक: **निर्दलीय विधायक राजो सिंह जो एक जमाने में डा० जगन्नाथ मिश्र के खासुलखास हुआ करते थे और मिश्र-सरकार में राज्यमंत्री थे, इन दिनों मुख्यमंत्री दुबे के बाहुबली बने हुए हैं। राजो मुख्यमंत्री दुबे के समक्ष प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुए हैं कि सरकारी संत को उन्हें 'वनवास' देना ही होगा। अब दुबे धर्मसंकट में हैं कि एकतरफ अपने चहेता बाहुबली राजो और दूसरी तरफ सरकारी संत हरिनारायणानंद—किस का साथ दें, किससे मुंह मोड़ें। राजो अडिग हैं कि हर हाल में स्वामी की छुट्टी शिकायत एवं निगरानी पर्षद् के उपाध्यक्ष पद से कर दी जाये। पर स्वामी भी कम नहीं। राजनीतिक पंडित कौतूहल से देख रहे हैं कि इस युद्ध में सरकारी संत मात देते हैं या राजो।**

संत की हैसियत: **स्वामी हरिनारायणानंद उत्तर प्रदेश के 'बाल्टी बाबा' की तरह कोई चमत्कारी नहीं**

और न ही तंत्रमंत्र की उन्हें सिद्धि प्राप्त है। पर संन्यासी हुलिये का लाभ स्वामी सदैव उठाते रहे हैं, चाहे जिस किसी भी दल या व्यक्ति की हुकूमत रही हो। बिन्देश्वरी दुबे जब बिहार में गद्दीनशीन हुए, तो 'सरकारी संत' के बहार के दिन आ गये। महीनों तक दुबे दरबार में अलख जगाने के पश्चात स्वामी ने अपने लिए एक दुधारू पद का इंतजाम दुबे से फिर पक्का करवाकर ही दम लिया। दुबे ने 'बिहार राज्य शिकायत एवं निगरानी पर्षद्' का उपाध्यक्ष पद स्वामी के कमंडल में डाल दिया। इस पर्षद् के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हुए। जाहिर है कि इस पर्षद् के पूरे मालिक स्वामी बन गये। बहरहाल, भ्रष्टाचार नियंत्रण के वास्ते स्वामी को एक अदद दफ्तर की सख्त जरूरत थी। इसलिए, बारह नंबर बेली रोड के बंगले में जिसमें डा० जगन्नाथ मिश्र अपने मुख्यमंत्रित्व काल में रहते थे और अब काबीना मंत्री सरयू मिश्र रहते हैं, उसी बंगले के अगले हिस्से का नामकरण १२-ए, बेली रोड कर स्वामी हरिनारायणानंद के 'भ्रष्टाचार निरोध' का दफ्तर बनाने का आदेश हुआ। सरयू मिश्र ने जब अपने बंगले का अगला हिस्सा स्वामी के कब्जे में जाते देखा, तो उन्होंने इसका विरोध किया। पर स्वामी के सामने दुस्साहस दिखाने के कारण मुख्यमंत्री दुबे ने सरयू को कड़ी डांट के साथ सख्त हिदायत दी कि स्वामीजी के सम्मान में हरगिज कोई कमी न होने पाये। लिहांजा, सरयू सहम गये और स्वामी का दफ्तर भी खुल गया। विधायक राजो सिंह ने विधान सभा में आरोप लगाया है कि स्वाभी इस संस्था के नाम पर अभियंताओं का भयादोहन कर धन की वसूली किया करते हैं। दूसरी तरफ परेशानहाल स्वामी घूम-घूमकर राजनीतिक गलियारे में इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। आखिर, राजो सिंह स्वामी के पीछे अचानक हाथ धोकर क्यों पड गये हैं। जानकारों का कहना है कि बिहार काबीना के कुछ वरिष्ठ भूमिहार मंत्री ही स्वामी के राजनीतिक हलचल से दुखी चल रह हैं, क्योंकि स्वामी अक्सर दिल्ली-दरबार की दौड़ लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री दुबे के साथ, कभी अकेले और कभी अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध शिकायत की गाथा दिल्ली-दरबार के खास नुमाइंदों को सुना आते हैं। मुख्यमंत्री दुबे ने भी जब इन मंत्रियों की बजाय स्वामी की बातों को ज्यादा अहमियत देना शुरू किया, तो स्वामी जरूरत से अधिक उत्साहित हो गये। लिहाजा, स्वामी के उत्साह को ठंडा करने के लिए ही राजो ने स्वामी के खिलाफ मुहीम छेड़ दी।

० अभयदान की याचना : तेजी से उभर रहे नये संत बाबा बलराम के सामने मुख्यमंत्री दुबेजी

संत पर संगीन आरोप :
निर्दलीय विधायक राजो सिह

स्वामी क्या नहीं हैं? भारत सेवक समाज के अध्यक्ष हैं, जिसके नाम पर अलग ही लंबा-चौड़ा कारोबार है। साथ ही 'अखिल भारतीय साधु समाज' के महामंत्री भी हैं। पटना में ही संस्कृत विद्यापीठ का भी उनका वृहद तामझाम है। वाकई, स्वामी बिहार राजनीति के व्यस्ततम संत हैं।

गोखुलपुर मठ का मामला : मूलतः सिवान जिले के बाशिन्दे स्वामी हरिनारायणानंद अपने चाचा मंगलदेव जी के प्रोत्साहन से संन्यासी जीवन में आये। बाद में नालंदा जिले के एकंगर सराय स्थित बड़ीमठ के महंथ बनने का जुगाड़ इन्होंने सफलतापूर्वक जमा लिया और फिर नालंदा जिले के ही हरनौत प्रखंड के गोखुलपुर मठ में भी इन्होंने हाथ-पांव फैलाना शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोखुलपुर मठ की जमीन को स्वामी ने अंधाधुंध बेचा। गोखुलपुर के लोगों के मुताबिक स्वामी के ही परामर्श पर मठ के तत्कालीन मर्हथ विशेश्वरानंदजी ने एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसके सचिव स्वामी बनाये गये और अध्यक्ष स्वयं विशेश्वरानंदजी बने। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस ट्रस्ट की डीड के अनुसार एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का निर्णय हुआ। वही विद्यापीठ स्वामी इनदिनों पटना में चला रहे हैं। संस्कृत शिक्षा के नाम पर यह विद्यापीठ क्या कर रहा है, यह सिवा स्वामी के शायद और कोई नहीं जानता। बहरहाल, बाद में गोखुलपुर मठ के महंत विशेश्वरानंद की हत्या रहस्यमय परिस्थिति में हो गयी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उसके बाद ही स्वामी ने गोखुलपुर मठ में मनमानी शुरू कर दी। नालंदा के सांसद विजय कुमार यादव ने गोखुलपुर मठ के सवाल पर अर्से से स्वामी के विरुद्ध मुहीम छेड़ रखी है। पर सरकारी संत का भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है!

स्वामी पर एक और निहायत संगीन आरोप है। कोशी परियोजना में चल रहे काम में भी स्वामी ने खासी दिलचस्पी ली थी। कोशी परियोजना में भारी घोटाला हुआ था। नतीजतन, १९६५ में इस घपले की जांच के लिए 'कपूर आयोग' का गठन हुआ था। कपूर आयोग ने अपने विस्फोटक प्रतिवेदन में घपले के प्रसंग में स्वामी हरिनारायणानंद की भी चर्चा की थी। अब जबकि स्वामी के खिलाफ हवा तेज है, तो 'कपूर आयोग' की स्वामी के विरुद्ध की गयी टिप्पणी को भी फिर से तूल दिया जा रहा है। नक्सली नेता और विधायक उमाधर सिंह ने कपूर आयोग की टिप्पणी बिहार सरकार को पेश करने को कहा। संसदीप कार्यमंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने दिल्ली स्थित आयुक्त को कपूर आयोग के १९६७ में दिये गये प्रतिवेदन की प्रति भेजने का आदेश भी दे दिया। राजनीतिक हल्कों में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या संसदीय कार्यमंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जो स्वामी के स्वजातीय ही हैं, स्वामी के खिलाफ चली मुहीम के असली सूत्रधार हैं।

बहरहाल, राजनीतिक पंडित दम साधे देख रहे हैं कि आखिर स्वामी का क्या हश्र होता है। यों, मुख्यमंत्री दुबे की अभी भी उन पर कृपा कायम है, इसलिए आसार है कि भगवा वस्त्र की लाज रह जायेगी।

अपने ऊपर बढ़ते संकट और जगन्नाथ मिश्र की सुधरती ग्रहदशा की खबर से मुख्यमंत्री दुबे साधु-संन्यासी व तांत्रिकों का चक्कर तेजी से लगा रहे हैं। अभी स्वामी के अतिरिक्त पटना के यारपुर मुहल्ले में बाबा बलराम नामक कथित संन्यासी के शरण में दुबे अक्सर पहुंचते हैं। बाबा बलराम पहले एक मामूली सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे। बाद में उन्होंने कई धंधे किये और कई पापड़ बेलने के बाद उन्हें लगा कि साधु का हुलिया सर्वोत्तम है। लिहाजा, पटना में इन दिनों अक्सर बाबा बलराम यज्ञ और कई पापड़ बेलने के बाद उन्हें लगा कि साधु का हुलिया सर्वोत्तम है। लिहाजा, पटना में इन दिनों अक्सर बाबा बलराम यज्ञ और होमादि करवाते हैं और बिहार राजनीति के दिग्गज राजनेता उनका चरण पकड़कर सत्ता की सुरक्षा का 'अभयदान' पाते हैं। इन दिनों स्वामी हरिनारायणानंद के बाद बाबा बलराम सरकारी संन्यासी के रूप में तेजी से उभरे हैं। पर एक राजनीतिक पंडित की टिप्पणी रोचक है कि बाबा बलराम स्वामी हरिनारायणानंद से तेज हैं, क्योंकि वह बगैर कोई राजनीतिक पद लिये अपना सारा काम साधते हैं, पर स्वामी हरिनारायणानंद राजनीतिक पद की प्राप्ति में ही फंस गये। फिलहाल, स्वामी विधान परिषद् की सदस्यता के लिए जहां जोर-शोर से 'तप' कर रहे थे, वहीं 'भ्रष्टाचार निगरानी' की कुर्सी को उनके कमंडल से निकालने का अभियान तेज है। दुबे दरबार के एक मुलाजिम कहते हैं, "भई, देखते चलिए, बाबा (बिन्देश्वरी दुबे) के दरबार में बाबाओं की लड़ाई...।

—विकास कुमार झा

मंत्रियों-विधायकों को 'जन-गण-मन' का पता नहीं

यदि आप अंगूठा टेक हैं, तो आप क्लर्क भी नहीं बन सकते, लेकिन आप यदि विधायक, सांसद या फिर मंत्री बनना चाहते हैं, तो आप को पढ़ाई-लिखाई की जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपने 'भाग्यविधाताओं' से सामान्य ज्ञान के सवालों के उत्तरों की अपेक्षा नहीं कर सकते। साहित्य, संस्कृति और धर्म-पुराण की बात करना तो और भी बेमानी है। लेकिन क्या हम उनसे यह अपेक्षा भी न करें कि वे हमारे राष्ट्रीय गौरव, गरिमा और सम्मान के प्रतीकों को जानें? क्या हम उनसे यह उम्मीद भी न करें कि उनको जन-गण-मन याद हो, 'बंदेमातरम' के अमर लेखक का नाम याद हो, यह पता हो कि राम और रावण महाभारत के पात्र हैं कि रामायण के? लगता है हमको यह अपेक्षा अपने रहनुमाओं से नहीं करनी चाहिए।

इस नाउम्मीदी का सबब है हमारा एक सर्वेक्षण, जो हमने बिहार में किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह थाह लेना था कि हम अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति कितने सजग हैं। इस सर्वेक्षण का आधार हमने अपने 'भाग्यविधाताओं' को बनाया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर हम यह फतवा तो नहीं देना चाहते कि ये जन-प्रतिनिधि राष्ट्रीय भावनाओं से शून्य हैं, लेकिन इतना जरूर जगजाहिर कर देना चाहते हैं कि हमारे भविष्य की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है, वे कितने 'महान' हैं। स्वाधीनता की चालीसवीं वर्षगांठ पर आयोजित इस सर्वेक्षण के तहत हमने टंकित प्रश्नावली इन जनप्रतिनिधियों के पास भेजी थी और अनुरोध किया था कि वे उत्तर अपने हाथ से लिख कर भेजें। हम आभारी हैं, इन जनप्रतिनिधियों के कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। 'माया' ने जो 'मामूली' पांच सवाल पूछे थे, वे इस प्रकार हैं:

१. आपके प्रिय राजनेता।
२. आपके प्रिय लेखक।
३. बंदेमातरम के रचयिता की और कौनसी कृति आपको प्रभावित करती है?
४. महाभारत का कौनसा पात्र आपको प्रभावित करता है?
५. 'जन-गण-मन' की कोई चार पंक्ति लिखें।

सबसे दिलचस्प, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि बिहार विधानसभा के तकरीबन ७५ प्रतिशत सदस्यों को राष्ट्रीय गान याद नहीं। कुछ दिलचस्प उत्तर इस प्रकार हैं:

दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के इंका विधायक रामचंद्र पासवान बंकिमचंद्र की जिस महत्वपूर्ण कृति से प्रभावित हैं—वह है 'गौरिया मठ'। पूर्वी चंपारण के सुगौली क्षेत्र से इंका विधायक सुरेश कुमार मिश्र को 'बंदेमारतम' के रचयिता की 'एकला चलो रे' नामक पुस्तक बहुत पसंद है। तारापुर के निर्दलीय विधायक शकुनि चौधरी को बंकिमचंद्र की 'गीतांजलि' बेहद पसंद है। बिहार के काबीना स्तर के मंत्री महावीर पासवान ने कुछ और भी मार्के की जानकारी दी है। वह लिखते हैं कि उन्हें बंकिमचंद्र की जो महत्वपूर्ण कृति पसंद है, वह है—"श्री रवींद्र नाथ ठाकुर के शांति निकेतन के मजार पर लिखे शब्द एकला चलो रे।"

विधान परिषद सदस्य विजय शंकर मिश्र को 'महाभारत' के जिस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, वह है—रावण। इसी तरह सुगौली के विधायक सुरेश मिश्र का उत्तर है कि महाभारत में उन्हें रामचंद्रजी सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। साहित्य का ज्ञान भी बिहार के विधायकों का अद्भुत है। मसलन, गुमला जिले के सिमडेगा क्षेत्र के भाजपा विधायक निर्मल कुमार बेसरा का उत्तर है कि साहित्य में उन्हें राजा हरिश्चन्द्र नामक लेखक सबसे प्रिय हैं। इसी तरह सिंचाई राज्यमंत्री सुशीला केरकेटा का उत्तर है कि उनके प्रिय लेखक 'देशभक्ति' हैं। अलोली क्षेत्र से लोकदल विधायक पशुपति कुमार को साहित्य में 'मुख्यमंत्री का आंचल' बहुत पसंद है। राष्ट्रगान के बारे में इन जनप्रतिनिधियों की कितनी जानकारी है, इसके कुछ नमूने तो यहां दिये ही जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की चालीसवीं वर्षगांठ पर हम इस नेतृत्व पर गर्व करें या शर्म करें यह आप स्वयं सोचें।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें। १. जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता (पूरा)
बंदे मातरम् पूरा याद नहीं है।

रसिकलाल ऋषिदेव
विधायक का हस्ताक्षर

रसिक लाल

६१ वर्षीय रसिक लाल ऋषिदेव अपने प्रिय राजनेता के उत्तर में लिखते हैं—मम्मता गांधी। पता नहीं यह मम्मता गांधी कौन हैं? बंदेमातरम के रचयिता की अन्य कृति के उत्तर में रसिक लाल लिखते है 'गीतांजलि'। रसिक लाल भी 'राष्ट्रगान' याद रखने की जहमत नहीं उठाते।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग
सब याद नहीं है।

विधायक का हस्ताक्षर

टेकलाल महतो

हजारी बाग के मांडू क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ४४ वर्षीय टेकलाल महतो भी राष्ट्रगान विस्मृत कर चुके हैं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

याद नहीं है।

विधायक का हस्ताक्षर

अयोध्या प्रसाद

बछवाड़ा के कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ४४ वर्षीय अयोध्या प्रसाद को महाभारत की कथा मालूम नहीं। बंकिमचंद्र कौन थे उन्हें नहीं पता और राष्ट्रगान की तो उन्हें एक पंक्ति भी याद नहीं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

पूरा गाना पसंद है।

पूरा गाना याद नहीं है।

विधायक का हस्ताक्षर

छेदी पासवान

३० वर्षीय छेदी पासवान रोहतास जिले के चेरानी क्षेत्र से लोकदल के विधायक हैं। छेदी भी स्वीकारते हैं कि राष्ट्रगान उन्हें याद नहीं

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

जनगणमन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
भूल गया हूँ।

विधायक का हस्ताक्षर

रामेश्वर यादव

सिकटी के इंका विधायक ६२ वर्षीय रामेश्वर यादव 'जन-गण-मन' भूल गये हैं।

प्रश्न नं0-4. "बंदे मातरम" के रचयिता की और किस कृति ने आपको प्रभावित किया है।

उत्तर:- श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर के (शांतिनिकेतन) आधार
पर लिखे [illegible]

महावीर पासवान

बिहार सरकार में कल्याण विभाग के काबीना मंत्री महावीर पासवान ने बंदेमातरम के रचयिता बंकिमचंद्र के लेखन के सम्बन्ध में कुछ नये रहस्योद्घाटन किये हैं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

पूरा याद नहीं है।

रवीन्द्र प्रसाद शाही

विधायक का हस्ताक्षर

रवींद्र प्रसाद शाही

सीतामढ़ी जिले के सुरसंड क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रवींद्र प्रसाद शाही भी राष्ट्रगान से अनभिज्ञ हैं।

अकाल राहत

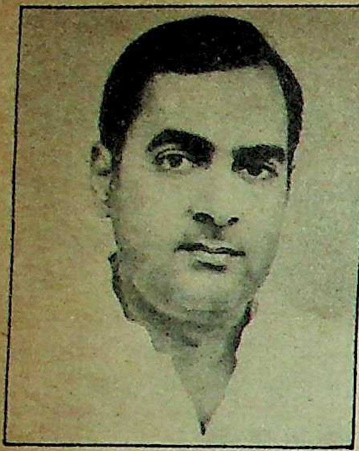

जून, 1987 में 18 लाख लोगों को रोजगार

पिछले दो वर्षों से लगातार सूखे और अकाल का सामना करने के बाद राजस्थान इस वर्ष फिर शताब्दी के भीषणतम अकाल की चपेट में है। शासन इस विपदा का मुस्तैदी से मुकाबला करने में जुटा है।

- पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक राहत कार्य।

  जून, 1987 तक 395.61 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत के 1,06,945 जन उपयोगी व स्थायी महत्व के कार्य स्वीकृत।
- माह जून, 1987 में राहत कार्यों तथा अन्य विभागीय कार्यों पर 18 लाख लोगों को रोजगार।

  राहत कार्यों पर लगे लोगों की यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।
- गत मई माह में मजदूरी के रूप में प्रतिदिन लगभग 1.54 करोड़ रुपये व्यय।
- अन्न व चारे की माकूल व्यवस्था। केन्द्र से प्राप्त 5 लाख टन गेहूं का वितरण। पशुओं के लिए 20 लाख क्विन्टल चारे की व्यवस्था जो गत वर्ष की तुलना में तीन गुनी है।
- पेयजल उपलब्धि के विशेष प्रयास। ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख कुओं के निर्माण व गहरा कराने का अभूतपूर्व कार्यक्रम।
- पंचायती राज व अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं से राहत कार्यों का निष्पादन।

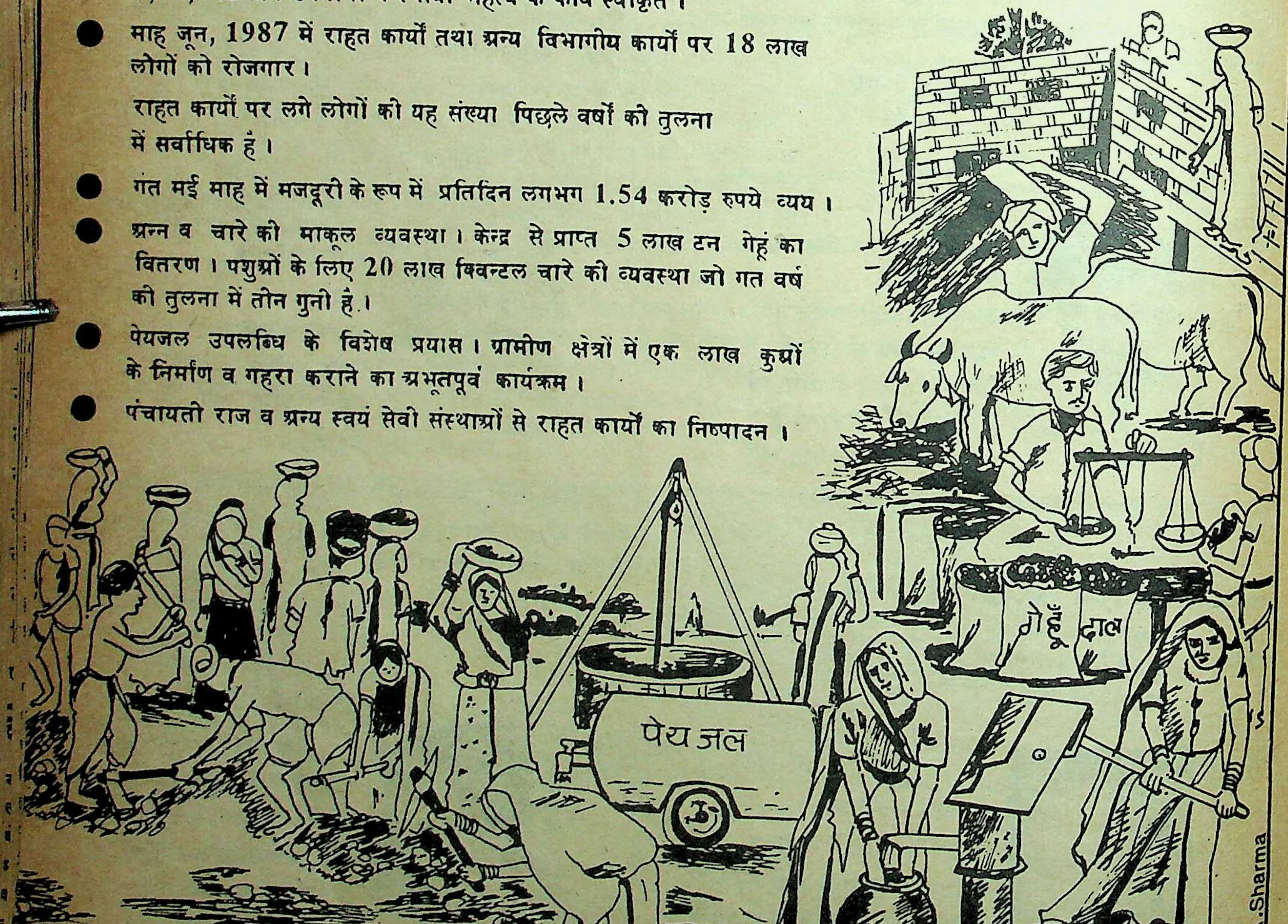

डी.आई.पी.आर.

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

जन· गन मन अधिनायक भारत।
भाग्य विधाता जव सुनना जागे तव
गाये जय गाथा।

विधायक का हस्ताक्षर

सत्यदेव सिंह
खगड़िया

सत्यदेव सिंह

खगड़िया – के इंका विधायक सत्यदेव सिंह ने राष्ट्रगान की ये दो पंक्तियां लिखीं।

प्रश्न नं०-5. राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

उत्तर:- जनगण गान नायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता; जय हे,
जय हे, जय हे।

जनक यादव

विधायक का हस्ताक्षर

[illegible]

जनक यादव

छपरा के स्वतंत्र विधायक जनक यादव इस प्रश्न के उत्तर में कि किस राजनेता के जीवन ने उन्हें प्रभावित किया है, अपना ही नाम लिखते हैं। जनक को भी 'राष्ट्रगान' याद नहीं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

जन गण मन अधिनायक जय भारत
भारत भाग्य विधाता –
(अभी याद नहीं है)

मोतीउर्रहमान

विधायक का हस्ताक्षर

मोतीउर्रहमान

ढाका से इंका विधायक ४० वर्षीय मोतीउर्रहमान को भी 'जन-गण-मन' याद नहीं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

पूर्ण प्रभावित करता है।
जन मन अधिनायक है; भारत भाग्य विधाता पंजाब सि

पशुपति कुमार

विधायक का हस्ताक्षर

पशुपति कुमार

खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र से लोकदल विधायक ३५ वर्षीय पशुपति कुमार विपक्ष के चर्चित नेता राम बिलास पासवान के अनुज हैं। 'राष्ट्रगान' वह भूल गये हैं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

जन- गण मन अधिनायक
जय हे भारत भाग्य विधाता

सिंधु, व्यास, झेलम - सतलज
राबी और चनाब

विधायक का हस्ताक्षर

परमानन्द ठाकुर
स०वि०स०

परमानंद ठाकुर

दरभंगा जिले के बहेड़ी क्षेत्र से ४२ वर्षीय इंका विधायक परमानंद ठाकुर ने राष्ट्रगान में कुछ नये संशोधन किये हैं।

राष्ट्रीय गान "जन-गण-मन" की कोई चार पंक्ति लिखें जो आपके मन को सबसे ज्यादा छूती है अगर पूरा गान आपको प्रभावित करता है तो पूरा भी कृपया लिखें।

मुखाग्र है।

12-7-87

विधायक का हस्ताक्षर

सरयू मिश्र

लघु सिंचाई विभाग के काबीना मंत्री सरयू मिश्र 'जन-गण-मन' की चार पंक्तियां नहीं लिख सके। बस एक पंक्ति लिखने के पश्चात मिश्रजी को अगली पंक्ति याद नहीं हो पायी।

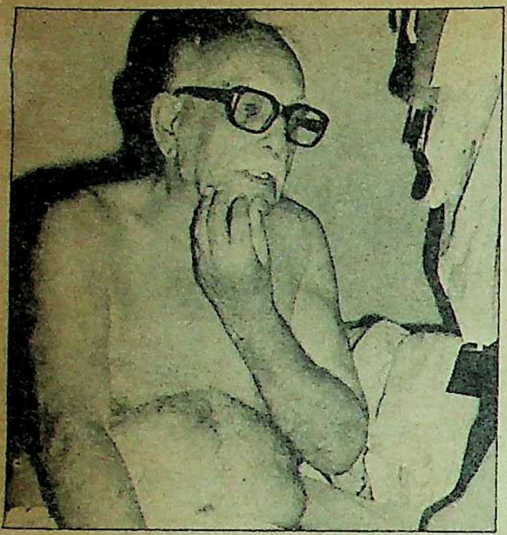

छाया : अमरेंद्र दुबे

हेक्टर एंगस ब्राउन

एम०एल०ए० नंबर-३२५

बिहार विधान सभा में एक एंग्लो-इंडियन हेक्टर एंगस ब्राउन ऐसे विधायक हैं, जिनका कोई चुनाव क्षेत्र नहीं है। जो बिना चुनाव लड़े, विधायक बनते हैं, जबकि विधानसभा की कार्यवाही में वह कोई सक्रिय हिस्सा नहीं लेते। राजनीति में रहते हुए भी वह राजनीति से कोसों दूर हैं। किसी से मिलते-जुलते भी नहीं—अकसर निपट अकेले रहते हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह १९६९ से विधायक हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। श्री ब्राउन एकांतवासी क्यों हैं? वह क्या करते हैं? राजनीति में उनको अहमियत देने का कारण क्या है? उत्तर तलाश रहे हैं, विकास कुमार झा :

हेक्टर एंगस ब्राउन कोई अंग्रेज नहीं हैं, पर बुर्राक गोराई और लंबी-चौड़ी कद-काठीवाले लगभग सत्तर वर्षीय ब्राउन महाशय खालिस अंग्रेज लगते हैं। वह न तो शुद्ध अंग्रेज हैं और न ही हिंदुस्तानी बाबुओं की नस्ल के ही। बिहार के सुदूर देहाती इलाकों से अपने काम के चक्कर में जब आम लोग अपने क्षेत्र के विधायक के पीछे-पीछे भटकते हुए विधानसभा परिसर में जाते हैं और अचानक जब वे, इन ब्राउन महाशय को विधानसभा की कार्रवाई में शरीक होने के लिए जाते हुए देखते हैं, तो एकदम से हकबका कर रह जाते हैं। सहसा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। देर तक वे तय नहीं कर पाते कि आखिर अंग्रेज-सा दीखने वाला यह आदमी बिहार के किस विधानसभाई क्षेत्र से विजयी होकर आता है? इस नस्ल की आबादी बिहार में वैसे कहीं है भी तो नहीं! तब क्या यह विधायक विधानसभा में 'एलिस के आश्चर्यलोक' का प्रतिनिधित्व करता है? सचमुच, आमलोग सिर थाम कर बैठ जाते हैं। कोई अनुमान काम नहीं करता। यहां तक कि बहुत-से विधायक भी ब्राउन के बारे में ठीक-ठीक नहीं जानते। इसके पीछे प्रमुख वजह यह भी है कि ब्राउन सिर्फ अंग्रेजी में ही बातें कर सकते हैं और बिहार के अधिकांश विधायक अपनी कमजोर अंग्रेजी के कारण ब्राउन से बातचीत करने का सिरदर्द मोल लेना नहीं चाहते। एक विधायक झल्ला कर कहते भी हैं, "यह अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी के सिवा कुछ समझता ही नहीं। यह लंदन की एसेंबली तो है नहीं।" ब्राउन १९६९ से विधायक होते आ रहे हैं और इस लिहाज से यह उनका छठा 'टर्म' है। पर गुजरे वर्षों में उनकी शैली में कोई तब्दीली नहीं आयी है। बेहद खामोशी से वह विधानसभा में आते हैं, कुछ देर चुपचाप अपनी सीट पर बैठते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उठकर चले जाते हैं। विधानसभा की किसी भी कार्रवाई में न वह दिलचस्पी लेते हैं, न उनके बारे में ही कोई दिलचस्पी रखता है।

विधायक कैसे बने : बिहार विधानसभा में कुल ३२४ विधायक खुले चुनाव में घोर जोर-आजमाइश के बाद आ पाते हैं, पर विधानसभा की निर्देशिका में दर्ज विधायकों के नाम की फेहरिस्त में ३२५ नाम दर्ज हैं। यही तीन सौ पच्चीसवें हैं, हेक्टर ब्राउन। वह बिहार विधानसभा के ऐसे इकलौते एंग्लो-इंडियन विधायक हैं, जिनका अपना कोई विधानसभाई चुनाव क्षेत्र नहीं हैं। हिंदुस्तान की सबसे अल्प आबादीवाले एंग्लो इंडियन समुदाय, जिसने सदैव संशय और उपेक्षा ही भोगी है, के प्रतिनिधि ब्राउन भी विधानसभा में निपट गुमनामी की स्थिति में ही हैं। भारत में बसे एंग्लो-इंडियन-समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद-७९ के तहत एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा में और एक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की विधानसभा में नामजद करने का प्रावधान किया गया है। लिहाजा, इसी प्रावधान का सुख बिहार में विगत १८-१९ वर्षों से ब्राउन महाशय उठा रहे हैं। एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं, "ब्राउन के अलावा अब तक कोई दूसरा उपयुक्त एंग्लो-इंडियन नहीं मिला। इसलिए रिक्त स्थान की पूर्ति की रस्म अदायगी ब्राउन के नाम से ही की जा रही है। आजादी के बाद से अब तक बिहार विधानसभा में ब्राउन तीसरे एंग्लो-इंडियन विधायक हैं। बिहार में सबसे पहले एंग्लो-इंडियन विधायक मनोनीत किये गये थे, एम० मौरिस, जो कभी ब्रिटिश राज्य में आई०पी०एस० अधिकारी हुआ करते थे। मौरिस के निधन के बाद श्रीमती ओसिया नामक एक महिला, जो वन-अधिकारी थीं, को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमती ओसिया जब अचानक इस दुनिया से कूच कर गयीं, तो फिर नये सिरे से एंग्लो-इंडियन नस्ल के किसी व्यक्ति की जोर-शोर से तलाश शुरू हुई और इसी के बाद ब्राउन महाशय को ढूंढ़ निकाला गया और एम०एल०ए० के पद पर मनोनीत कर दिया गया। ब्रिटिश राज्य में ब्राउन सेटलमेंट अफसर हुआ करते थे। उनकी इस नौकरी का अधिकांश समय मुजफ्फरपुर और हजारीबाग में बीता। नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के कुछ माह पूर्व ब्राउन को सहरसा जिले का कार्यकारी जिलाधिकारी बनने का भी अवसर हासिल हुआ।

एकाकी जीवन : ब्राउन अविवाहित हैं और स्थायी-रूप से हजारीबाग स्थित पुराने तर्ज के अपने छोटे-से खूबसूरत मकान में एक नौकर के साथ निपट एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। पटना में उन्हें प्रेसीडेंट चैम्बर में महज एक कमरेवाला छोटा-सा तंग सरकारी फ्लैट आवंटित है, जिसमें सिर्फ विधानसभाई सत्र के दौरान वह आकर टिकते हैं। पटना के इस फ्लैट के दरवाजे पर अकसर ताला झूलता रहता है, पर ऐसी बात नहीं कि कमरे में ब्राउन नहीं होते। इसका रहस्योद्घाटन उनके नौकर ने रोचक ढंग से किया, "मैं जब सब्जी आदि खरीदने बाहर जाता हूं, तो ब्राउन साहब को बाहर से ताला बंद करके जाता हूं। यह उन्हीं का निर्देश है। इसकी वजह है कि वह किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते।" पूरे हजारीबाग में मात्र चार एंग्लो-इंडियन परिवार हैं। ब्राउन कहते हैं, "परिवार के नाम पर बस मेरी एक बहन थी और मेरी बहन को, बस एक लड़की थी, प्रिया। बहन तो बहुत पहले गुजर गयी। प्रिया मुझे प्रिय थी। इस संसार में अपना कहने को, बस वही थी। प्रिया ने फिल्म अभिनेता इंदर ठाकुर से शादी की थी और उसको एक बच्चा भी था। पर कनिष्क हवाई दुर्घटना में डेढ़-दो वर्ष पहले इंदर-प्रिया और उनका बच्चा चल बसे। अब, अपना कहने को मेरा कोई नहीं रह गया। किसी अंतरंग की दस्तक अब मेरे दरवाजे पर नहीं होती। मैं फिल्में कभी नहीं देखता, पर एंग्लो-इंडियन के जीवन पर आधारित फिल्म '३६ चौरंगी लेन' की तारीफ मैंने सुनी है। उस फिल्म की निर्देशिका के प्रति मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने भारत में एकाकी जीवन की व्यथा से जूझ रहे एंग्लो-इंडियन की स्थिति को पूरी सामर्थ्य से व्यक्त किया है। सचमुच एंग्लो-इंडियन की व्यथा गूंगी है। कोई इसे महसूस नहीं करता। ऐसा लगता है मानो इस नस्ल के लोगों का जन्म ही एक बड़ी भूल है। किसी को उसकी जरूरत ही नहीं। मेरा कम ही लोगों से सरोकार है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश सिंह, कृषि मंत्री लहटन चौधरी और युवा विधायक, बसंत सिंह मेरे परिचितों में-से हैं। विधानसभा में आज तक मैं बस एक बार बोला हूं, पर वह भी व्यर्थ, क्योंकि हिंदी में मैं बेहद कमजोर हूं और

विधानसभा में अंग्रेजी बोलने पर पाबंदी है। इसलिए दस-पंद्रह वर्षों से मुंह बंद कर विधानसभा में बैठने को मैं मजबूर हूं। ब्राउन व्यंग्य से कहते हैं, 'प्वाइंट आफ आर्डर' और 'जीरो आवर' जैसे कई अंग्रेजी शब्द विधानसभा में प्रचलित हैं। पता नहीं, इसका प्रयोग धड़ल्ले से क्यों होता है ? यह तो हिंदी नहीं।"

ब्राउन बिहार के अकेले ऐसे विधायक हैं, जिन्होंने फोन की सुविधा मिलने के बावजूद अब तक फोन नहीं लगवाया है। वह कहते हैं, "टेलीफोन को मैं विज्ञान का सबसे घटिया अन्वेषण मानता हूं। यह बेवजह परेशानी पैदा करनेवाला डिब्बा है। मैं जिन दिनों सरकारी सेवा में   था, उन दिनों भी मैंने टेलीफोन कभी नहीं लगवाया।"

शौक : ब्राउन महोदय को संगीत से बेहद लगाव है। अमरीकी उपन्यास पढ़ने का खास शगल है और हजारीबाग में अपने एक एकड़ जमीन के टुकड़े में, वह फल उपजाने का खास शौक रखते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं, "मैं जन्मजात घुमक्कड़ हूं। जिस दिन मैं घूमना बंद कर दूंगा, समझिएगा मेरी मौत आ गयी। ट्रेन और बसों में घूमना मुझे विशेष पसंद है। इन यात्राओं में लोगों के बहस-मुबाहिसे रोचक होते हैं। अकसर ट्रेन-बसों में यात्री एम०एल०ए० लोगों को जमकर गालियां दिया करते हैं और बीच-बीच में मेरी राय भी पूछते हैं, क्योंकि वे मेरा हुलिया देखकर कल्पना तक नहीं कर सकते कि मैं भी एक एम०एल०ए० हूं। इसलिए ऐसी यात्राएं दिलचस्प होती हैं।"

क्या मनोनीत एम०एल०ए० होने के कारण आपको अन्य एम०एल०ए० जैसे सारे अधिकार हासिल हैं या कुछ फर्क है इसके जवाब में ब्राउन कहते हैं, "बस दो मौकों पर फर्क है। एक तो मैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता और दूसरे, राज्यसभा के चुनावों में मतदान नहीं कर सकता। अन्यथा एक एम०एल०ए० के सारे अधिकार मुझे प्राप्त हैं। सभी विधायकों को पांच किलोमीटर सड़क बनवाने का अधिकार प्राप्त है। इसे वह जहां चाहे, बनवा सकता है। पटना स्थित एंग्लो-इंडियन संचालित 'डानबास्को स्कूल' के लोग मेरे पास आये और कहा कि स्कूल के पास सड़क नहीं, तो मैंने अपने कोटे से उसे बनवा दिया।"

समस्याएं : बिहार में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका खुलासा करते हुए ब्राउन कहते हैं, "शिक्षा का अभाव और लुप्त होती जा रही सांस्कृतिक गरिमा एंग्लो-इंडियनों की सबसे बड़ी समस्या है। नयी पीढ़ी में शिक्षा हासिल करने की रुचि लगभग समाप्त-सी हो गयी है।"

बिहार में एंग्लो-इंडियन समुदाय का एक संगठन है, 'वेलफेयर ऐंड सोशल एसोसिएशन फार एंग्लो-इंडियंस।' इस संगठन की सात शाखाएं हैं—रांची के समीप मैकलेक्सी गंज, चक्रधरपुर, खगौल, पटना, गोमो, मोसीबानी और जमशेदपुर। ब्राउन ही इसके अध्यक्ष हैं। वह कहते हैं, "इस संगठन के जरिये हम भरसक एंग्लो-इंडियन समुदाय की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कई वर्ष पूर्व, रांची से कुछ दूर, खेलारी में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोगों ने सहकारी स्तर पर एक कालोनी 'मैकलेक्सीगंज' नाम से स्थापित की। पर बाद में वहां की सुंदर सहकारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। इसकी वजह थी कि एंग्लो-इंडियन जन्मजात खर्चीली प्रवृत्ति के होते हैं। लिहाजा, इस समुदाय में सहकारी व्यवस्था की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। एंग्लो-इंडियन सांस्कृतिक विघटन की भी व्यथा भोग रहे हैं। उनके संगीत, उनका नृत्य, कम्युनिटी हॉल, सब खतम-सा हो गया है।"

लोकसभा में दो मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य हैं, एक तो फ्रैंक एंथोनी और दूसरे श्रीमान ए०इ०टी० बेरो। फ्रैंक एंथोनी 'आल इंडिया एंग्लोइंडियंस एसोसिएशन' के अध्यक्ष भी हैं।

बहरहाल, देश की अल्पमत आबादी के बिहारी प्रतिनिधि, ब्राउन बिहार की जाति-प्रधान राजनीति में क्या अहमियत रखते हैं, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। किसी राजनीतिक दल से ब्राउन का ताल्लुक भी नहीं। खामोश, ताला झूलते कमरे में बंद, बाहरी माहौल और राजनीतिक उखाड़-पछाड़ से दूर, बिहार के विधायक नंबर तीन सौ पच्चीस का साथी उनका अपना अकेलापन है। पर बिहारी राजनीति के एक दिग्गज नेता उसांसे भरकर कहते हैं, "ब्राउन सबसे खुशनसीब हैं। कम-से-कम उन्हें हर पांच साल पर हाथ जोड़कर जिस-तिस के पास वोट मांगने के लिए भटकना नहीं पड़ता, वह बिना चुनाव क्षेत्र के एम०एल०ए० जो ठहरे!" ■

जलन · खुजली · खून
बवासीर के पहले लक्षण
फौरन इलाज शुरु कीजिए
ऑपरेशन की नौबत मत आने दीजिए.

बवासीर आम बीमारी है. पर लापरवाही से समस्या गंभीर हो सकती है. हो सकता है ऑपरेशन की नौबत ही आ जाए.

बवासीर का प्रभावी इलाज है प्रेपरेशन-एच *, जिसकी सिफारिश विदेशों में प्रमुख डॉक्टर करते हैं.

प्रेपरेशन-एच, औषधियुक्त मलहम का अनोखा फार्मूला, न सिर्फ जल्द ही पीड़ा और खुजली से आराम दिलाता है, बल्कि असल में सूजन कम करता है व स्नायुओं को सिकोड़ता है. प्रेपरेशन-एच चिकनाहट दे कर शौच की तकलीफ भी कम करता है.

প্রিপারেশন এইচ
অর্শের ঔষধ
PREPARATION H
OINTMENT
Shrinks piles
Stops itch
Relieves pain
FOR EXTERNAL USE ONLY
STORE IN A COOL DRY PLACE

*Licensed user of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

GM-PH-87-HN

हरिदेव जोशी

मुख्यमंत्री जाते-जाते बच गये !

यों तो हरियाणा चुनाव के बाद ही हरिदेव जोशी पर हमला तेज हो गया था, लेकिन अरुण नेहरू के दल से निष्कासन के बाद तो यह लगने लगा था कि श्री जोशी के दिन अब गिनती के हैं, लेकिन असंतुष्टों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया। असंतुष्ट क्या-क्या चालें चलते रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उन चालों को काटने में क्या महारत दिखायी है—

बता रहे हैं : **ओम सैनी**

छाया : गोपाल संगर

असंतुष्टों को एक और मात : मोहसिना किदवई और जोशी

हरियाणा में कांग्रेस-इ की पराजय और केंद्र में सांसद अरुण नेहरू के सत्तारूढ़ दल से निष्कासन के बाद यह पक्का समझा जाने लगा था कि मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के दिन पूरे हो गये। असंतुष्टों ने नये सिरे से हमला बोला। उनका आरोप था कि जो हाल कांग्रेस-इ का हरियाणा में हुआ है, वही हाल श्री जोशी के निकम्मे शासन के कारण राजस्थान में भी हो सकता है। श्री जोशी को अरुण नेहरू का कृपापात्र माना जाता रहा है, इसलिए जब उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया, तो श्री जोशी पर खतरा और सघन हो गया।

प्रदेश में यह बात बड़े साफ तौर पर कही जाती है कि श्री जोशी को १९८५ में मुख्यमंत्री-पद दिलवाने में सांसद एवं पूर्वगृहमंत्री अरुण नेहरू, माखनलाल फोतेदार तथा आलाकमान के वर्तमान महामंत्री नवल किशोर की अहम भूमिका रही थी। कहा तो यहां तक जाता है कि अरुण नेहरू और माखनलाल फोतेदार पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से अपने राजनीतिक खर्चे की पूर्ति के लिए चौथ वसूल करते थे। पर जब अमिताभ बच्चन से शिवचरण माथुर की साठगांठ हुई, तो उन्होंने चौथ देना बंद कर दिया। ऐसे में शिवचरण माथुर जब भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में फंसे, तो श्री नेहरू और फोतेदार ने अपना हिसाब उन्हें हटवाकर चुकता कर लिया। हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पुरानी परंपरा को कुछ ज्यादा जिम्मेदारी से निभाया। उनके अटल रहने का राज लोगों को इस परंपरा-पालन में ही नजर आता है।

मुख्यमंत्रियों की नियति : पूरे देश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस-इ का मुख्यमंत्री अपने ही दल के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किया जाता। यह नापसंदगी छोटे मंत्रिमंडलों के गठन के कारण और बढ़ी है। राजस्थान में दो दशक तक स्व० मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बने रहने का सुख मिला था और इस सुख की वजह थी, हर असंतुष्ट को मंत्री बनाना। पर जब से कांग्रेस-इ संगठन में चुनावों को तिलांजलि देकर मुख्यमंत्री आलाकमान की ओर से थोपे जाने लगे हैं, तब से मुख्यमंत्री इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता कि वह किसको मंत्री बनाये, किसको नहीं और उसके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हों। सब कुछ 'ऊपर' से तय होता है। लेकिन असंतोष का सारा गुस्सा मुख्यमंत्री पर ही निकाला जाता है। इसका जरिया है, हाईकमान को मुख्यमंत्री के खिलाफ ज्ञापन देना। सत्ता-सुख से वंचित कांग्रेसी इसी एक सूत्री कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से लगे रहते हैं।

इनका असर भी होता है। जनता राज के बाद जब राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तेरह महीने के उनके शासन में उन्हें लगातार असंतोष का सामना करना पड़ा। शिवचरण माथुर उनके पीछे लगे रहे, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी अपने 'फार्म हाउस' अथवा विधानसभा की लाबी में बैठे कसमसाते रहे। अंततः पहाड़िया हिंदी कवयित्री महादेवी वर्मा का अपमान कर 'दिल्ली की

देवी' के कोपभाजन बने। मुख्यमंत्री की गद्दी शिवचरण माथुर के हाथ लगी, तो पहाड़िया हटानेवाली मुहीम के सहयोगी राजीवप्रिय विधायक नरेंद्र सिंह भाटी उनके विरुद्ध हो गये। माथुर विरोध की इस आंधी से तानाशाह की तरह निपटने की तैयारी कर ही रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुरसी वर्तमान मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को सौंपनी पड़ी। आज जब श्री जोशी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें दोनों पूर्वमुख्यमंत्रियों (पहाड़िया-माथुर), प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अशोक गहलोत तथा ज्यादातर विधायकों की ज्ञापन-मार का सामना करना पड़ रहा है।

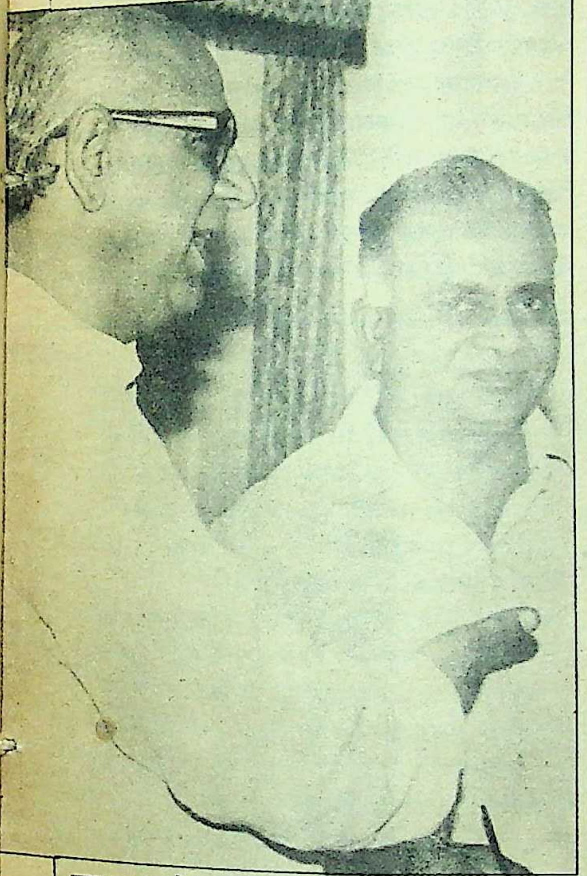

खूब कान भरे : भाटिया और माथुर

सुखाड़िया कूटनीति के अनुयायी मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी राज्य विधानसभा में एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो १९५२ से लगातार चुनकर पहुंच रहे हैं। आठ साल के अंतराल के बाद उन्हें दुबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है। उनके बस में होता, तो वह अपने विरोधियों को बड़ी आसानी से मंत्रिमंडल में जगह दे, उनका विरोध समर्थन में बदल लेते। दिवंगत सुखाड़िया ऐसा ही किया करते थे, पर आलाकमान की लगायी सीलिंग के कारण उन्हें कई जोखिमों में से गुजरना पड़ रहा है।

असंतुष्टों का भोज : इस बार राष्ट्रपति चुनाव के माहौल के साथ ही असंतुष्टों की गोलबंदी प्रारंभ हुई। हरियाणा में हुई पराजय से विर्चालित आलाकमान के सम्मुख असंतुष्टों के गठजोड़ ने अपनी बात खुलकर कहने का फैसला किया। इधर परदे के पीछे चलनेवाली राजनीति के सितारों को बेनकाब करने के लिए मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 'भोज आयोजन' की कूटनीति अपनायी।

६ जुलाई को मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर राष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में विधायकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। विधायक दल की औपचारिक बैठक में अनुपस्थिति का अर्थ आलाकमान क्या लगायेगा, इसे मुख्यमंत्री जोशी खूब समझ रहे थे। उन्हें यह भी मालूम था कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर बहाना बनाकर भोजन से अलग रहेंगे। हुआ भी यही। शिवचरण माथुर जयपुर में रहते हुए नहीं आये, जबकि पहाड़िया दिल्ली से देर रात लौटे। अखबारों ने अगले दिन इस अनुपस्थिति को दर्ज किया, जिसे विधायकों की बैठक को संबोधित करने आनेवाले केंद्रीय नेताओं ने गौर से पढ़ा। उन्हें यह भी पता लगा कि कांग्रेस-इ के ११५ विधायकों में से १०३ मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित दावत में उपस्थित थे। अनुपस्थित बारह विधायकों में से दो ने बीमारी की वजह से माफी चाही थी, बाकी बगैर कुछ कहे नदारद थे। मुख्यमंत्री ने दावत-कूटनीति के तहत अपने निवास पर घोषणा की थी कि ये दावतें विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से हर रोज होंगी, जिनमें सभी का उपस्थित होना लाजमी है।

दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से जब मुख्यमंत्री के भोज में उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया, तो पहाड़िया तो देर होने का बहाना कर गये, लेकिन शिवचरण माथुर ने खुलकर कहा कि मुख्यमंत्री जोशी के निवास पर बुलायी गयी बैठक उनके द्वारा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का आडंबर भर था। उन्होंने १० जुलाई को आलाकमान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होनेवाली बैठक को वास्तविक बैठक करार देते हुए उसमें उपस्थित होने की बात कही।

इस बीच मुख्यमंत्री जोशी ने १० जुलाई को होनेवाली बैठक का स्थान अपने निवास स्थान से बदलकर खासाकोठी कर दिया। दस बजे शुरू होनेवाली इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी के महामंत्री रघुनन्दन लाल भाटिया पर्यवेक्षक की हैसियत से व तीन केंद्रीय मंत्री—योगेन्द्र मकवाना, ब्रह्मदत्त, श्रीमती मोहसिना किदवई—उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्वमुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर एक साथ आये। मुस्कानें बिखेरीं, बंद हाल में नेताओं के भाषण सुने और फिर खाने का बहिष्कार कर जाने लगे। जगन्नाथ पहाड़िया केंद्रीय मंत्री मकवाना से गुफ्तगू करना चाहते थे, जबकि शिवचरण माथुर उनसे तुरन्त चलने का आग्रह कर रहे थे। इसी दौरान संवाददाताओं ने शिवचरण माथुर से खाने के बहिष्कार का कारण जानना चाहा। उनका कहना था, "अकाल और सूखे से पीड़ित राजस्थान में इस तरह के सरकारी आयोजन मैं पसंद नहीं करता।" केंद्रीय मंत्री मकवाना को जब पता लगा कि पहाड़िया बगैर भोजन किये शिवचरण माथुर के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने उन्हें रोक लिया। माथुर को अकेले लौटना पड़ा। सारे दृश्य ने केंद्रीय नेताओं और अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी के महामंत्री की निगाहों में शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया को असंतुष्टों के नेताओं के रूप में स्पष्ट कर दिया।

उधर मुख्यमंत्री जोशी ने आलाकमान के प्रतिनिधियों के सामने दावा किया कि वह दल के ११५ विधायकों के अलावा पन्द्रह और विधायकों के मत आर० वेंकटरमण के पक्ष में डलवायेंगे। मतदान का नतीजा आने पर पता लगा कि श्री वेंकटरमण को १२६ मत प्राप्त हुए। कांग्रेस—इ के पक्ष में आठ निर्दलीय विधायकों के मत तो समझे जा रहे थे, पर छह मत किस दल के आये, यह खोज का विषय बना हुआ है। वैसे मुख्यमंत्री श्री जोशी के लोकदल-ब और जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ऐसे ताल्लुक हैं कि शीर्षस्थ नेता भी वेंकटरमण को वोट दे गये हों, तो आश्चर्य की बात नहीं समझी जायेगी! बहरहाल, विपक्ष के नेताओं ने अपनी ईमानदारी के दावे किये हैं, पर राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा अपनी अलग ही कहानी कहता है, लेकिन राजस्थान के असंतुष्टों ने राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम तक इंतजार नहीं किया। जिस तरह मुख्यमंत्री जोशी ने राष्ट्रपति चुनाव में मत हासिल करने के लिए भोज

यकीन दिलाने की कोशिश : पहाड़िया, केंद्रीय मंत्री ब्रह्मदत्त, मकवाना और मोहसिना किदवई

कूटनीति का उपयोग किया था, ठीक उसी तरह असंतुष्टों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के तुरन्त बाद दो गुटों में बंटकर भोज-आयोजन किया। 'माया' को इस आयोजन की खबर मतदान के दौरान ही लग गयी थी। जयपुर से निर्वाचित कांग्रेस-इ के विधायक शिवराम शर्मा नाराज विधायकों के कान में फुसफुसाकर पांच सितारा होटल मानसिंह में भोजन एवं वार्ता हेतु आमंत्रित कर रहे थे। शिवराम शर्मा असंतुष्टों के पहाड़िया—माथुर एवं भाटी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल के उपमुख्यसचेतक अश्क अली टाक ने अपने निवास पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समर्थित एवं मुख्यमंत्री से नाराज विधायकों का भोज आयोजित किया था।

दोनों आयोजनों में बुनियादी फर्क यह था कि जहां विधायक शिवराम शर्मा के यहां आनेवाले लोग मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलना चाहते थे, वहीं उपमुख्यसचेतक के यहां आमंत्रित लोग अशोक गहलोत की हैसियत दिखाने और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री बदलने के हामी थे। बहरहाल, माथुर-पहाड़िया समर्थकों ने अशोक गहलोत को हटाने के सम्बन्ध में इस वक्त खामोशी धारण कर रखी है, पर गहलोत-समर्थक जानते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ नेतृत्व-परिवर्तन के हामी लोग, उन्हें भी पसन्द नहीं करते।

असंतुष्टों का भोज : दस जुलाई की संध्या के इस आयोजन में मानसून की पहली भारी वर्षा ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। बहरहाल, २१ विधायक अश्क अली टाक के यहां एकत्रित हुए और २२ विधायक, शिवराम शर्मा के आयोजन में पहुंचे। ठण्डी खुशनुमा संध्या में मंहगी सुरा के साथ आयोजन शुरू हुआ। एक राष्ट्रीय दैनिक, संवाद-समितियों और स्थानीय अखबारों के अपने विश्वस्त पत्रकारों को आयोजन की खबर देने के लिए शामिल किया गया। अगले दिन, आयोजकों की इच्छानुसार खबरें प्रकाशित हुईं। लेखन में कमजोर कांग्रेसियों के लिए कुछ सधे हुए पत्रकारों ने असंतोष के मुद्दों को ज्ञापन में संवारा। दावा किया गया कि राज्य में कांग्रेस-इ के विधायकों का बहुमत प्रान्तीय नेतृत्व से असन्तुष्ट हो गया है।

जयपुर के कांग्रेस-इ विधायक शिवराम शर्मा के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया और माथुर शामिल होने वाले थे, पर वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में गांधीवादियों को सुरा-ग्रहण करने से परहेज करना होता है, इसलिए उन्हें आशीर्वाद तक सीमित रखा गया। अगले दिन शिवराम शर्मा ने बयान जारी कर कहा, "हमारी बैठक में उपस्थित विधायक एवं राज्य मंत्रि-मण्डल के तीन सदस्य मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को उनके पद से हटाये जाने के पक्ष में हैं।" शर्मा के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए राज्य में नेतृत्व-परिवर्तन का संकल्प लिया गया। बैठक में, पूर्वमंत्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, गोविंद सिंह गूजर, श्रीमती नीलिमा शर्मा, श्रीमती कमला भील, माधोसिंह दीवान, ईश्वर लाल सैनी इत्यादि उपस्थित बताये गये। 'माया' ने शिवराम शर्मा से उन मंत्रियों के नाम जानने चाहे, जिनका समर्थन असंतुष्टों को प्राप्त है, लेकिन उन्होंने इन मंत्रियों के नाम बताने से इनकार कर दिया। बहरहाल, उनका दावा था कि ८०-८५ विधायक राज्य के वर्तमान नेतृत्व से असंतुष्ट हैं।

शिवराम शर्मा के अनुसार बैठक में उपस्थित विधायकों का मानना था कि मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण राज्य में कांग्रेसजनों का मनोबल गिर रहा है। विपक्षी विधायकों के पैर जम रहे हैं और कांग्रेस-इ विधायकों के पैर उखड़ रहे हैं। उनके अनुसार विधायकों ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य में समय रहते नेतृत्व परि-

---

साक्षात्कार / हरिदेव जोशी

जनता क्या महसूस करती है, इसको अहमियत देता हूं

माया : आपके सवा दो साल के शासन में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की आम शिकायत रही है कि आप उनकी अनदेखी करते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं को विशेष तरजीह देते हैं?

जोशी : यह बात मेरे खिलाफ बनायी हुई और फैलायी हुई है। हां, यह बात तो सही है कि पुराने विधायक होने के कारण जो पुराने लोग हैं...पार्टी लीडर हैं, उनसे मेरी जान-पहचान काफी है। अन्तरंगता भी है और कुछ लोग पिछले चुनावों में जीतकर आये हैं...इन्डिपेन्डेन्ट (निर्दलीय) जोकि दरअसल कांग्रेस के थे...टिकिट नहीं मिलने के कारण और अन्य कारणों से जीत करके आ गये...वे मुझे पहचानते हैं। राजनीतिक नेता भी पहचानते हैं। इसलिए उनके साथ में मेरी खुलावट है। दूसरे, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि दूसरी पार्टी में कोई आदमी है, उससे सामाजिक और व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं रखे जाने चाहिए। जैसे प्रोफेसर केदार हैं, नाथूरामजी हैं, कामरेड श्योपत सिंह हैं या भैरूंसिंहजी हैं। इन सबसे हमारा मिलना-जुलना हो जाता है, मगर पार्टी की कीमत पर नहीं...नाट एट द कॉस्ट आफ द पार्टी। सही बात तो यह है कि ये लोग बहुत कम काम बताते हैं। और रह गया सवाल मेरा उनको अपने पक्ष में करने का तो आपने देखा होगा कि पिछले दो साल के मेरे शासन के दौरान जितने बड़े आन्दोलन हुए हैं, उतने बड़े पहले कभी नहीं हुए।

माया : माना पार्टी की कीमत पर आप सम्बन्ध नहीं बनाते, पर दूसरे दलों के जिन लोगों के मत आपने राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा के अपने उम्मीदवार के लिए हासिल किये, उसे क्या कहेंगे?

जोशी : ऐसा है कि राज्यसभा के चुनावों में प्रत्याशियों ने भी अपने एफर्टस् (व्यक्तिगत प्रयास) किये थे और अभी प्रेसिडेन्ट के चुनाव में हमारा केन्डिडेट (उम्मीदवार) इतना जबर्दस्त था कि दूसरा कोई अपोजिशन में आदमी ही नहीं था।

माया : आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और वे बड़े गैरजिम्मेदाराना ढंग से पेश आते हैं। मसलन आपकी स्वास्थ्य मंत्री ने सोजत में एक डाक्टर द्वारा गुर्दे बदलने व बेचने के भाजपा के आरोप को बगैर जांच के सही मान लिया?

जोशी : मुझे मालूम नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया है। जवाब तो वही दिया होगा जो विभाग ने लिख कर दिया होगा।

माया : उन्होंने विधानसभा में माना था कि हां गुर्दा बदला गया।

जोशी : नहीं, यह था कि गुर्दे का आपरेशन किया गया। ('माया' ने विधान सभा की कार्यवाही स्वयं देखी थी, बयान वही था जो सवाल में दर्ज है)।

माया : कहा जाता है कि आपने उन विधायकों को सरकारी लाभों से वंचित किया है जो पार्टी संगठन में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। मसलन माधोसिंह दीवान, सी०पी० जोशी और दोनों पूर्वमुख्यमंत्री, क्या यह सच है?

जोशी : सी०पी० जोशी (नाथद्वारा विधायक) तो मेरा मित्र है। मैं उसकी कोंसटिट्यूंसी में दो बार दौरा कर चुका हूं। कहीं किसी को किसी लाभ से वंचित रखने का प्रश्न ही नहीं है...और फिर दोनों पूर्वमुख्यमंत्रियों को किसी लाभ से महरूम रखने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्कूल खोलना या विकास का काम करना यह सब तो नीचे से तय होता है। इसमें मैं किसी को महरूम रखूं, प्रश्न ही नहीं है।

माया : पूर्वमुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का ऐसा आरोप है कि उनके विधानसभा क्षेत्र को अकाल राहत कार्यों में तरजीह नहीं दी जा रही?

जोशी : मुझसे भी बड़े बुजुर्ग ने इस तरह के बयान पर टिप्पणी की है। कोई आदमी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री पहले रह लेता है और अब नहीं है, तो वह यों सोचता है कि सब खराब हो रहा है। (सुखाड़िया मंत्रिमण्डल में वित्तमंत्री रहे माथुरदास माथुर ने पूर्वमुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के सोच के बारे में यह टिप्पणी पिछले दिनों की थी।)

माया : आपके लिए यह भी कहा जाता है कि आप पार्टी के प्रदेश संगठन को अपने मातहत बनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए गुटबंदी को तरजीह देते हैं?

जोशी : गुटबंदी मेरे द्वारा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं संगठन को किसी भी हालत में छोटा बनाकर रखने का तो सोच ही नहीं सकता,

वर्तन नहीं किया गया, तो कांग्रेस-इ को राजस्थान में भी हरियाणा की तरह ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

अश्क अली टाक के यहां हुई बैठक में उपस्थित विधायकों में नाथद्वारा के कांग्रेस-इ विधायक सी०पी० जोशी, संसदीय सचिव चन्द्र शेखर शर्मा, राजेन्द्र चौधरी, प्रणवीर व्यास, बाबूलाल बैरवा व राज्य-मंत्रिमण्डल की सदस्य श्रीमती बीना काक प्रमुख थीं। श्रीमती बीना काक ने अगले दिन अपनी उपस्थिति को मात्र जासूसी करार दे दिया। उनका कहना था कि वह तो यह देखने गयी थीं कि बैठक में कितने विधायक मौजूद थे।

बहरहाल, अश्क अली टाक के यहां से समवेत स्वर में सभी विधायकों ने प्रधानमंत्री के प्रति पूरी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के हालात के बारे में वे कुछ नहीं कहेंगे, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। उन्हें तकलीफ थी कि राज्य में पार्टी की छवि सुधारने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत से राय क्यों नहीं लेते ? इन लोगों को जहां अपना काम न होने की शिकायत राज्य प्रशासन से थी, वहीं ये लोग राजस्वमंत्री श्रीमती कमला, कृषि राज्य मंत्री छोगाराम बाकोलिया और स्वायत्त शासन राज्यमंत्री, सुजान सिंह यादव के व्यवहार से भी नाराज थे। बैठक में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर जहां राज्य सरकार की आलोचना की गयी, वहीं यह चेतावनी भी दी गयी कि यदि हालात में सुधार नहीं किया गया, तो राजस्थान में कांग्रेस-इ की स्थिति हरियाणा से भी बदतर हो जायेगी। बैठक में यह नाराजगी भी दर्ज हुई कि राजस्थान में कोई विधायक किसी मुद्दे पर अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री परेशानियां शुरू कर देते हैं। इस सन्दर्भ में नाथद्वारा की विशेष रूप से चर्चा की गयी।

भोज की कूटनीति : एक तरफ जहां असंतुष्टों के यह आयोजन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर वास्तविक नेता मसलन, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया उन नेताओं को साथ लेने के लिए लंच आयोजित कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री जोशी के खिलाफ हैं। पर, साथ ही पहाड़िया माथुर को भी अपना नेता नहीं मानते। पूर्व मुख्यमंत्री, शिवचरण माथुर ने जोशी हटाओ मुहीम में जिस तरह से अन्य पूर्वमुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को साथ लिया, उसी तरह से अपने जिले भीलवाड़ा के सांसद गिरधारी लाल व्यास को लंच पर बुलाकर मतभेद दूर किये। नतीजा यह हुआ कि कल तक के दुश्मन आपस में मित्र बन गये। सांसद गिरधारी लाल व्यास कुछ समय पहले तक शिवचरण माथुर के कट्टर विरोधी और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के विशेष समर्थक थे। माथुर और व्यास के बीच भीलवाड़ा जिले की राजनीति में नेतृत्व को लेकर विवाद रहा है। इसी तरह जब पहाड़िया मुख्यमंत्री थे, तो शिवचरण माथुर ने उनके खिलाफ पूर्व राजीव प्रिय विधायक नरेन्द्र सिंह भाटी, शिवराम शर्मा, पूर्व विधायक सुरेन्द्र व्यास और पूर्वविधायक श्रीराम गोटेवाला के साथ मिलकर उन्हें हटाने का अभियान वर्तमान तर्ज पर ही चलाया था। चाणक्य को आदर्श मानते हुए तीनों ने जोशी को हटाने के लिए एका किया और तय किया कि दिल्ली को राजस्थान की स्थिति से अवगत कराया जाये।

असंतुष्टों का यह काफिला जब दिल्ली पहुंचा, तो बड़ा उत्साह था। विधायक शिवराम शर्मा ने जिन मंत्रियों के उनके साथ होने की घोषणा की थी, उनमें से एक, विधि मंत्री हीरालाल देवपुरा के होने का अनुमान इससे लगता है कि वह राज्य सरकार के अतिथिगृह में असंतुष्टों की अगवानी करने के लिए पहले से मौजूद थे। इन लोगों के हौसले उस वक्त ठण्डे

क्योंकि बेसिकली (बुनियादी रूप से) मैं संगठन का आदमी हूं। मैं वर्षों तक पी०सी०सी० (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) का प्रेसिडेन्ट (अध्यक्ष) रहा हूं। इतने वर्षों शायद लोग विधानसभा के सदस्य भी नहीं रहे होंगे। इसलिए संगठन को सरकार की तुलना में छोटा बनाने का प्रश्न नहीं है। अलबत्ता यह कि मुझे संगठन को आदर देना चाहिए और पार्टी को सरकार को। यह परस्पर चीज है।

माया : आपके उपमुख्यसचेतक अश्क अली टाक ने युवा असंतुष्टों को भोज पर आमंत्रित कर आप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन को तरजीह न न देने का आरोप लगाया है।

जोशी : ह्विप्स आर दी आइज् ऐंड इयर्स ऑफ द पार्टी...(सचेतक पार्टी का कान और आंख होते हैं।) यह एक कहावत है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां क्या है ?

माया : कहा यह भी जाता है कि आप उन पत्रकारों, विधायकों और अफसरों को विशेष लाभ देते हैं जो आपकी मनोवांछित मुहीम में सहयोग करते हैं ? पत्रकारों को सरकारी कोठियां दी गयी हैं, जबकि यह आम सुविधा नहीं हैं ?

जोशी : केवल एक समाचार पत्र को दी है। बाकी मेरे जमाने में किसी को नहीं दी गयी। बाकी लोगों को किसने दी आपको याद है ? (शिवचरण माथुर के मुख्यमंत्रित्व के दौरान उपलब्धियों का बयान करने के एवज में कुछ पत्रकारों को यह लाभ दिया गया था।)

माया : आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया है, जिन्हें भ्रष्ट कहकर कांग्रेस-इ के टिकट से वंचित किया गया था। क्या यह सच है ?

जोशी : एक का भी नाम बता दीजिए आप, जिसको मैंने प्रश्रय दिया हो ?

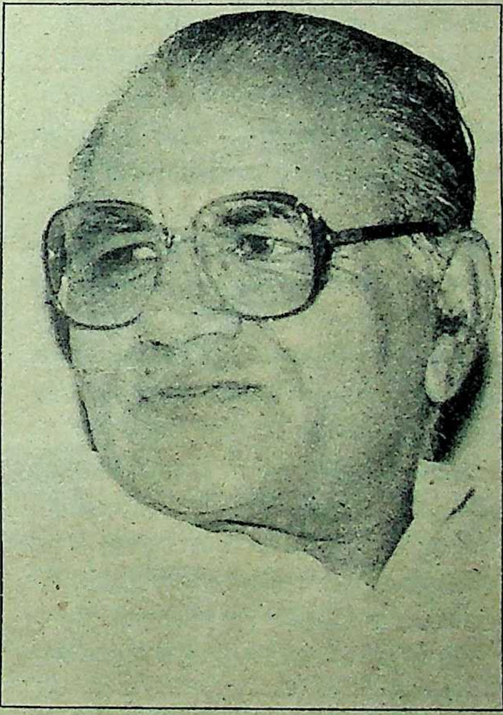

माया : कांग्रेस-इ नेतृत्व पूरे देश के साथ-साथ राजस्थान में भी अपनी जमीन खो रहा है, क्या आप ऐसा नहीं मानते ?

जोशी : आज सच तो ऐसा नहीं है। अब तक तो जितने भी चुनाव राजस्थान में हुए हैं, कांग्रेस जीती है। आगे की मैं नहीं जानता। मेरे बस में जब तक होगा तब तक ऐसा होने नहीं दूंगा।

माया : पूर्वमुख्यमंत्री शिवचरण माथुर आपकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं। साथ ही आपके प्रशासन को निकम्मा बताते हुए आपको एक असफल मुख्यमंत्री मानते हैं ?

जोशी : अब वह तो कोई ऐसी संस्था नहीं हैं, जिससे मुझे कोई सर्टिफिकेट लेना हो। मुझे सर्टिफिकेट राजस्थान की जनता से लेना है और राजस्थान की जनता क्या महसूस करती है, इसको मैं अहमियत देता हूं। मैं जब गांवों में घूमता हूं, तब आम कांग्रेस-कार्यकर्ता क्या महसूस करता है, एम०एल०ए० क्या महसूस करता है...इसको अहमियत देता हूं। आज ईमानदारी की बात तो यह है कि सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता मुक्त हृदय से कहता है कि इन दो वर्षों के फेमिन (अकाल) के अन्दर जो काम हमने किये हैं... आप भी थे, एक दो बार मेरे साथ ? जिसमें लोगों ने कहा था कि ऐसे काम कभी नहीं हुए।

माया : पूर्वमुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के अनुसार प्रान्त का हरिजन आपसे खुश नहीं है और आपकी सरकार को हरिजन विरोधी मान रहा है ?

जोशी : कांग्रेस की कोई भी स्टेट (राज्य) अगर हरिजन विरोधी है, तो वह सरकार कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का सैद्धान्तिक रूप से यह कमिटमेंट है...हरिजन के अपलिफ्टमेन्ट (ऊपर उठाने) का और उन्हें बराबरी का दर्जा समाज में देने का और उनके विकास का। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक अगर किसी काम में मैंने व्यक्तिगत रुचि ली है, तो वह है—आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान का काम।

(मुख्यमंत्री से 'माया' ने जब नाथद्वारा से सम्बन्धित प्रश्न और कांग्रेस से निष्कासित विभिन्न नेताओं पर टिप्पणी का आग्रह किया, तो वह उसे टाल गये।)

भेंटकर्ता : ओम सैनी

क्यों नाराज हैं, गहलोत-पहाड़िया-माथुर

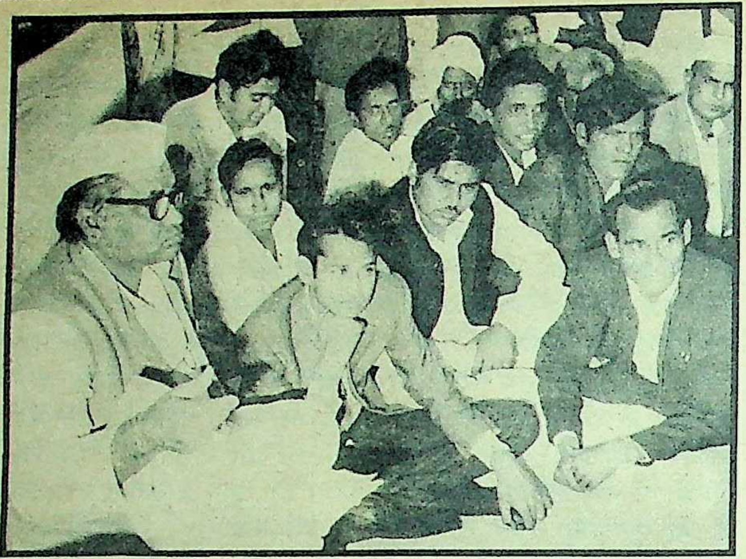

कभी ऐसा था : अशोक गहलोत और जोशी

राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत के रिश्ते एक जमाने में बड़े मधुर रहे हैं । पूर्व में श्री जोशी १९७३ में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस-इ के छात्र-संगठन के अध्यक्ष थे । छात्र-अध्यक्ष के रूप में श्री गहलोत की जरूरतें मुख्यमंत्री वैसे ही पूरी किया करते थे, जिस तरह आजकल के युवा नेताओं की करते हैं ।

बाबूजी और बेटे जैसा रिश्ता रहा है दोनों का ।

पर वक्त के साथ अशोक गहलोत युवा प्रधानमंत्री के युवा चहेते होकर पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में आये और फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गये ।

लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में श्री जोशी अशोक गहलोत को नहीं सुहाये, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में श्री जोशी ने उन्हें पसन्द नहीं किया । बताया जाता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से इसलिए नाराज हैं कि वह 'मिस्टर क्लीन' के पूर्वघोषित मापदण्डों पर खरे नहीं उतरते । मुख्यमंत्री नये-पुराने व भ्रष्ट तथा ईमानदार होने के विशेषणों की वजह से कांग्रेसियों में फर्क नहीं करते । संगठन और सरकार के बीच जिस तालमेल की कल्पना अशोक गहलोत के जेहन में है, जोशी उसे किताबी मानते हैं । दोनों की समझ का यह फर्क जब अशोक गहलोत सिद्धान्त के मीटर से नापते हैं, तो झगड़ा खड़ा होता है, जो आज भी बरकरार है ।

ठीक इसी तरह पूर्वमुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को प्रशासनिक सूझ-बूझ का दम्भ परेशान कर रहा है । सुखाड़िया सरकार में इन्हें ईमानदार होने का खिताब हासिल हुआ था । बाद में अन्तरात्मा की आवाज पर वह प्रगतिशील बने और प्रगतिशील होने के आधार पर दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद बख्शा था । इसे हासिल करने के बाद इन्होंने उपलब्धियों के ऐसे आंकड़े ईजाद किये, जिनका लाभ आम आदमी को कम मिला, लेकिन वे इनकी कुरसी की सुरक्षा के लिए कारगर रहे । भरतपुर के विधायक मानसिंह की हत्या के साथ इनके पीछे जो दुर्भाग्य लगा, वह आज तक उनका पीछा कर रहा है ।

शिवचरण माथुर आज भी अपने आंकड़ा ज्ञान पर इतने रीझे हैं कि वह यह मान ही नहीं सकते कि मुख्यमंत्री जोशी उनसे बेहतर तरीके से राज्य-प्रशासन चला सकते हैं । यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है, वह आंकड़ों की महारणी (राजस्थान में पण्डितों के यहां बच्चों को जोर-जोर से बोलकर पढ़ाया जाता है, इस तरीके को महारणी कहते हैं) बोलते हुए, नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं और केवल अपने हक में करते हैं ।

इस मामले में जगन्नाथ पहाड़िया कुछ माह पूर्व तक अपनी खामोशी के लिए विख्यात थे । श्री पहाड़िया राजस्थान से ऐसे सांसद रहे हैं, जिन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में सबसे ज्यादा रहने का मौका मिला है । दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी की असीम कृपा से उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका प्राप्त हुआ और जुबान के गलत उपयोग (हिंदी की विख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा का अपमान करने) के कारण विधानसभा में विधायक बनके बैठना पड़ा है । आलाकमान उनका महत्व समझता है, इसलिए उनकी अनपढ़ पत्नी को राजस्थान से राज्यसभा में खपाये हुए है ।

पिछले दिनों तक उनकी चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री के पक्ष में बयान देने की जरूरत तक हुआ करती थी, पर अब वह मुख्यमंत्री की मुखालफत के लिए विख्यात हो रहे हैं । ऐसी कौन सी वजह है, जिसने श्री पहाड़िया को मुख्यमंत्री श्री जोशी की मुखालफत करने के लिए मजबूर कर दिया ? 'माया' से उन्होंने बताया कि हरिजनों पर बढ़ रहे अत्याचारों के लिए वह जोशी प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं । "लेकिन हरिजनों पर अत्याचार तो लम्बे अरसे से हो रहे हैं, आप अब तक खामोश क्यों थे ?" इस सवाल के जवाब में श्री पहाड़िया का कहना था कि मैं दलहित में खामोश रहा हूं । पर वास्तविकता इससे परे है । श्री पहाड़िया की खामोशी जून माह में उस वक्त टूटी, जब सवाईमाधोपुर जिले के मण्डावर थाने के अन्तर्गत आनेवाले गांव रशीदपुर में उनकी ससुरालवालों की दाब-धौंस का जवाब गांववालों ने सख्ती से दिया । पांच हजार की आबादीवाले इस गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की काफी संख्या है । श्रीमती शांति पहाड़िया के दो साले और तीन भतीजे अपने प्रभावी रिश्तों के कारण अनुसूचित जाति के लोगों के लिए समस्या बने हुए थे । श्रीमती शांति पहाड़िया के खटीक जाति के भाई-भतीजों ने कोली जाति के अन्य परिवार के एक लड़के को मारपीटकर उसकी साइकिल और घड़ी छीन ली थी । पिटनेवाला लड़का जब अपने भाई के साथ छीनी हुई चीजें वापस लेने गया, तो दोनों को पीटकर घर में बंद कर दिया गया । लेकिन इनके खिलाफ गांववाले एक हो गये और उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा । मई माह की यह घटना मुख्यमंत्री जोशी के लिए परेशानी का सबब बन गयी । यह सच है कि घटना के बाद श्रीमती पहाड़िया के रिश्तेदारों के साथ ज्यादती हुई है, जिसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी और जमानत के मामले पर फैसला देते हुए लिखा है ।

इस सारे मामले में श्रीमती पहाड़िया मुख्यमंत्री से उन लोगों पर कार्यवाही करने की मांग कर रही थीं जो वास्तव में पीड़ित थे । मुख्यमंत्री का मौन देखकर श्रीमती पहाड़िया ने हरिजनों पर अत्याचार सम्बन्धी एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा । इस पत्र के बाद रशीदपुर में पुलिस के माध्यम से स्थिति शांतिपूर्ण हुई । पर जगन्नाथ पहाड़िया हरिजनों पर अत्याचार का सूत्र लेकर जोशी सरकार के खिलाफ खड़े हो गये ।

जोशी सरकार ने भी जगन्नाथ पहाड़िया का असली चेहरा लोगों के सामने पेश करने के लिए ऐसा मामला खोला है, जिससे पता लगता है कि 'हरिजन नेता' कितने साफ-सुथरे हैं । श्री पहाड़िया ने अगस्त, १९८१ से नयी दिल्ली के पण्डारा रोड स्थित बीकानेर हाउस परिसर में स्थित सरकारी दफ्तर पर जबरन कब्जा कर रखा है । कब्जा तब किया था, जब श्री पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ।

राजस्थान और मध्यप्रदेश के अन्तरराज्यीय सिंचाई एवं विद्युत मण्डल की इस इमारत का निवास के रूप में इस्तेमाल करने के बावजूद श्री पहाड़िया ने इसके बिजली-पानी के बिल नहीं चुकाये । जब बिलों का भुगतान नहीं हुआ, तो नयी दिल्ली नगर निगम ने २७ मई, १९८६ को इमारत के वास्तविक मालिकों यानी कोटा कलेक्टर को सूचना भेजी । इस सूचना में कहा गया कि २७ मार्च, १९८१ से २७ दिसम्बर, १९८४ तक का पानी-बिजली का ११ हजार, ९७२ रुपए, ४५ पैसे जमा नहीं करवाये । यह बात राज्य सरकार को साल भर से ज्ञात थी, लेकिन इसे उजागर तभी किया गया है, जब जगन्नाथ पहाड़िया ने जोशी सरकार की मुखालफत शुरू की ।

—ओम सैनी

अश्क अली टाक

सत्तारूढ़ दल के उपमुख्यसचेतक अश्क अली टाक ने अपने निवास पर प्रदेश कांग्रेस-अध्यक्ष समर्थित एवं मुख्यमंत्री से नाराज विधायकों का भोज आयोजित किया था।

शिवराम शर्मा

अगले दिन कांग्रेस-इ विधायक शिवराम शर्मा ने बयान जारी कर कहा, "हमारी बैठक में उपस्थित विधायक एवं तीन मंत्री जोशी के हटाये जाने के पक्ष में हैं।"

हो गये, जब आलाकमान ने एक साथ शुक्ला, नेहरू और खान को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी।

उधर, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाना प्रारम्भ कर दिल्ली में आलाकमान को असंतुष्टों की नीयत से अवगत कराया। जब असंतुष्ट दिल्ली दरबार में प्रधानमंत्री को तीन पृष्ठों का ज्ञापन दे, श्री जोशी को हटाने की मांग कर रहे थे, तभी मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपने शासन की उपलब्धियों की पन्द्रह पृष्ठों की एक पुस्तक जारी की। मुख्यमंत्री जोशी ने माथुर-पहाड़िया के आरोपों का जवाब अपने शासन की उपलब्धियों से दोनों पूर्वमुख्यमंत्रियों के राज के दौरान हुई प्रगति से तुलना करके दिया। जहां, पूर्वमुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों के ढोल पीटा करते थे, वहीं श्री जोशी ने अपनी उपलब्धियों वाली पुस्तक को 'हमारे विनम्र प्रयास' शीर्षक से प्रस्तुत किया। पुस्तक में, जोशी प्रशासन के सवा दो साल के कार्यों के विस्तृत विवरण के साथ सन् १९८० से ८५ तक छठी योजना की तुलनात्मक उपलब्धियों का लेखा-जोखा दर्ज था। इन पांच सालों में, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। इन लोगों के नामों का जिक्र किये बगैर मुख्यमंत्री श्री जोशी ने आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि अकाल राहत कार्यों में जितना आगे उनका प्रशासन है, माथुर-पहाड़िया तो उसके आस-पास भी नहीं टिकते।

असंतुष्टों को मात : तीव्रता से बदलते दिल्ली के घटनाचक्र से राजस्थान के असंतुष्ट कांग्रेसी विधायक स्तब्ध थे। असंतुष्टों को प्रधानमंत्री का दर्शन लाभ जरूर हुआ, पर मुख्यमंत्री जोशी के खिलाफ 'हम देखेंगे' से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। असंतुष्टों की पिटती हालत देखकर मुख्यमंत्री जोशी ने अपने में आस्था रखनेवाले विधायकों से आलाकमान को तार भिजवाये। इनमें जोशी-नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मांग की गयी कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के विरुद्ध खुली मुहीम चलानेवालों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कांग्रेस-इ के एक सौ पन्द्रह विधायकों में से चालीस ने श्री जोशी में आस्था व्यक्त कर दी थी।

हालात अचानक मुख्यमंत्री श्री जोशी के इतने पक्ष में चले गये कि उन्होंने अपनी ओर से असंतुष्टों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। इस मुहीम में पहला वार उन्होंने सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस-अध्यक्ष अशोक गहलोत के युवा अनुयायियों पर करवाया। राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस-इ की कार्यकारिणी के पुनर्गठन के नाम पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के०सी० विश्नोई ने अपने संगठन के उपाध्यक्ष रघु शर्मा और संगठन मंत्री राजीव अरोड़ा तथा पाली शहर के युवक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश मेहता व जोधपुर शहर के अध्यक्ष कर्णी सिंह इन्दा को अचानक उनके पदों से हटा दिया। ये चारों लोग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक बताये जाते हैं। कहा जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवल किशोर शर्मा ने गहलोत समर्थकों को हटाने के लिए प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा था। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निष्कासनों की पुष्टि करवाने का आश्वासन दिया था। पर २० जुलाई को इनके निष्कासन के आदेश हुए और २१ जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तार द्वारा इनको बहाल करने का आदेश दे दिया।

दरअसल, असंतुष्टों से लड़ाई में मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कमजोर पक्ष मानते हैं, यही वजह थी कि प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक के०सी० विश्नोई से जल्दबाजी में गहलोत समर्थकों को संगठन से अपदस्थ करवा दिया। वास्तविकता यह है कि आज भी सांसद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री का विश्वास हासिल किये हुए हैं। निष्कासितों की पुनर्बहाली, इसका एक प्रमाण है। बहरहाल, बदलते माहोल में मुख्यमंत्री से उम्मीद रखनेवाले विधायक आस्थाओं के तार दे रहे हैं, तो कोई असंतुष्टों के नेताओं पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए अपने को उनसे अलग कर रहा है। सवाल है कि असंतुष्टों की मुख्यमंत्री श्री जोशी से नाराजगी की वजह क्या है ? इसके जवाब में, कहा जाता है कि कुछ विधायक श्री जोशी से महज इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने शिवचरण माथुर के खिलाफ मुहीम में उनका साथ दिया था और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन्हें अपने मंत्रिमंडल में ले लेंगे, पर उन्होंने नहीं लिया। कांग्रेस-इ में ज्यादातर विधायक यह मानकर चलते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हर अफसर उनकी मरजी का लगेगा। उनकी राजनीति की बजट-पूर्ति करना इन अफसरों की जिम्मेवारी समझी जाती है। मुख्यमंत्री ने इस सन्दर्भ में विपक्ष के नेताओं की जहां मनोकामना पूरी की है, वहीं कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों को तरसाया है। नेतृत्व परिवर्तन चाहनेवाले विधायकों में ऐसे लोगों का बहुमत है। यही वजह है कि जिसे मुख्यमंत्री ने कुछ करने का आश्वासन दिया, उसने आलाकमान को मुख्यमंत्री में आस्था का तार दे दिया।

दरअसल, आज राजस्थान में हर दल का विधायक चुनाव-लहर, जात-समर्थन अथवा जोड़-तोड़ से विधानसभा की सदस्यता पाता है। दलों के कार्यक्रम कागजों तक सीमित होते हैं। आम लोगों की उनमें रुचि नहीं होती। समस्याएं जब जनता को बाध्य करती हैं, तो वह खुद एकत्रित होती है। दलों के नेता आते हैं और अपना झण्डा लगाकर उसे अपना कार्यक्रम बना लेते हैं। जब राजनीतिक दलों की सक्रियता का यह आलम हो, तो लाभ सत्ताधारी दल को मिलता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस-इ द्वारा जनाधर खोने जैसी बात पैदा नहीं होती। निश्चित रूप से चर्चा में कांग्रेस-इ लोकप्रियता खो रही है, पर प्रदेश में विपक्ष इतना एकजुट नजर नहीं आता कि कांग्रेस-इ को आंदोलन से सत्ताच्युत कर दे। ऐसी स्थिति में, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी कांग्रेस-इ के पास ऐसा कारगर व्यक्तित्व हैं, जो अपने दल के लिए भीड़ जुटा सकते हैं, वक्त पड़ने पर विपक्ष को खरीद सकते हैं। उन्होंने आलाकमान को राज्यसभा की तीसरी सीट हासिल करने व राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के १४ मत दिलाकर यह सिद्ध किया है। दूसरी ओर, राज्य के राज्यपाल वसंत दादा पाटिल ने आलाकमान को मुख्यमंत्री जोशी के राजनीति में कुशल होने का प्रमाण-पत्र दिया है। ऐसी स्थिति में, असंतुष्टों के आरोप आलाकमान को असरदार नजर नहीं आयेंगे।

—ओम सैनी

विद्याचरण शुक्ल

निष्कासन के बाद जमीन की तलाश

शक्ति-प्रदर्शन: निष्कासन के बाद पहली दफा रायपुर में विद्या भैया का काफिला

एक वक्त था, जब केंद्र और मध्य प्रदेश की राजनीति में विद्याचरण शुक्ल की तूती बोलती थी, लेकिन राजीव गांधी के सत्तारोहण और अर्जुन सिंह के चमकने के बाद वह निरंतर धूमिल पड़ते चले गये। अब उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। 'छत्तीसगढ़' 'विद्या भैया का गढ़' माना जाता है। निष्कासन के बाद अपना जोर दिखाने के लिए वह पहली दफा यहीं-यानी रायपुर पहुंचे। श्री शुक्ल की इस यात्रा के संदर्भ में मध्य प्रदेश की राजनीति के रुख को परख रहे हैं

सुधीर सक्सेना

कांग्रेस-इ से अपने निष्कासन के बाद, १६ जुलाई को इंडियन एयरलाइंस के बोइंग विमान से विद्याचरण शुक्ल जब पहली बार अपने गृहनगर रायपुर पहुंचे, तब आकाश मेघाच्छादित था और अच्छी खासी बारिश हो रही थी। माना हवाईअड्डे के बाहर सौ से ऊपर कारों, जीपों, बसों, मेटाडोर, ट्रकों और दुपहिया वाहनों की भीड़ थी। इन गाड़ियों में श्री शुक्ल के समर्थक रायपुर, भिलाई, बसना, धमतरी और महासमुंद आदि स्थानों से माना आये थे। स्वागत को आतुर भीड़ में नेता कम थे, कार्यकर्ता ज्यादा। भीड़ में औरों के अलावा परंपरागत लाल वर्दी पहने कुलियों की एक टोली भी थी, जो 'विद्या भैया जिंदाबाद' के नारे लगा रही थी। माना और रायपुर के बीच लगे बैनरों में श्री शुक्ल को छत्तीसगढ़ का खेवैया बताते हुए उनका प्रशस्ति-गान किया गया था, लेकिन हवाईअड्डे के बाहर एक बैनर ऐसा भी लगा था, जिसमें श्री शुक्ल को 'छतीसगढ़ के देवीलाल' की संज्ञा दी गयी थी।

उस दोपहर विमान से सबसे पहले उतरनेवाले यात्री थे, स्वयं सांसद विद्याचरण शुक्ल। जनताकाल को छोड़कर श्री शुक्ल १६५७ से रायपुर अथवा महासमुंद से सांसद हैं। इस दरम्यान वह सैकड़ों मर्तबा रायपुर आये होंगे, लेकिन इतना जोशीला स्वागत उनका पहले कभी नहीं हुआ था। उत्साह का आलम यह था कि सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं और अवरोधों को ठेंगा दिखाते हुए उनके समर्थक तुमुल निनाद के साथ हवाईपट्टी तक पहुंच गये और उन्हें सिर-आंखों पर बिठा लिया। माना हवाईअड्डे से श्री शुक्ल अपने समर्थकों—पूर्व विधायक तरुण चटर्जी और सुभाष धुप्पड़ के साथ—खुली जीप में सवार हुए। अमूमन उन्हें माना से रायपुर में बूढ़ापारा स्थित अपने आवास तक पहुंचने में आधा घंटा से ज्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन उस रोज बारिश, फूलमालाओं, ठौर-ठौर अगवानी, अभिनंदन और जिंदाबाद के सिलसिले ने ऐसा माहौल पैदा किया कि उन्हें बूढ़ापारा तक पहुंचने में तीन घंटे का वक्त लग गया। विद्याचरण शुक्ल को उनके समर्थक और नजदीकी लोग प्रेम और अपनत्व से 'विद्या भैया' कह कर पुकारते हैं और श्री शुक्ल को यह संबोधन पसंद भी है। १६ जुलाई को विद्या भैया जब हवाईअड्डे से घर पहुंचे, तो तरबतर थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून था और यह सुकून संभवतः इस बात का था कि उनकी बिरादरी के विधायकों व कुर्सियों पर आसीन मंत्रियों ने उन्हें भले ही बिसरा दिया हो, लेकिन आम कार्यकर्ताओं ने पार्टी की खुली चेतावनी के बावजूद उनका पलक-पांवड़े बिछाकर स्वागत किया था।

आघात: पूर्व में रायपुर और अब महासमुंद से निर्वाचित सांसद विद्याचरण शुक्ल पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विर्वासन के शिकार थे। एक वक्त केंद्र और प्रदेश की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी, मगर संजय गांधी और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के अवसान तथा कालांतर में राजीव गांधी के सत्तारोहण ने केंद्र में तथा अर्जुन सिंह के कूटनीतिक चातुर्य ने मध्यप्रदेश में उन्हें शनैः-शनैः कमजोर कर दिया। उनके अग्रज श्यामाचरण शुक्ल कांग्रेस की देहरी पर एकबार लटके, तो आज भी लटके हुए हैं। इन कारणों से प्रदेश की राजनीति पर शुक्ल गुट की पकड़ काफी ढीली हुई। इसके बाद भी यह समझना या सोचना गलत होगा कि प्रदेश की राजनीति से विद्याचरण का गुट तिरोहित हो गया। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की सरकार की बात करें, तो तीन मंत्री खुलेआम कलतक विद्या भैया के नुमाइंदे माने जाते थे और इन तीनों मंत्रियों—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री डा० कन्हैया लाल शर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री चित्रकांत जायसवाल और जन शक्ति नियोजन राज्य मंत्री विट्ठल भाई पटेल—ने विद्या भैया के प्रति अपनी निष्ठा को श्री शुक्ल के पार्टी से निष्कासन के पहले तक कभी छिपाया भी नहीं। सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों में पाठ्य पुस्तक निगम के वीरेंद्र तिवारी, निर्यात निगम के मनोहर बैरागी, अंत्यवसायी निगम के लक्ष्मी नारायण इंदूरिया और हाउसिंग बोर्ड की मैमूना सुल्तान का नाम कुछ समय पहले तक विद्या भैया की राजनीतिक बिरादरी से जोड़ा जाता था। विधायकों में

जयाबेन, कुमारी विमला वर्मा, श्रीमती जमुना देवी, रामचंद्र वाजपेयी, शिव नेताम, काकू भाई तथा सांसदों में दिलीप सिंह भूरिया, के०एन० प्रधान, परसराम भारद्वाज, बालकवि बैरागी, श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी, अरविन्द नेताम, कु० पुष्पासिंह, रामेश्वर नीखरा, एन०के० शर्मा को विद्या भैया के नजदीक माना जाता है। टिकट वंचित नेताओं और पिटे हुए मोहरों में श्रीनिवास तिवारी, अच्युतानंद मिश्र, शिवकुमार श्रीवास्तव, विजय मोहन तिवारी, कृष्णपाल सिंह आदि को श्री शुक्ल के खेमे में गिना जाता है। ऊर्जा विकास निगम के वयोवृद्ध अध्यक्ष विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे भी शुक्ल बंधुओं के काफी नजदीक रहे हैं। अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उपमुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि एवं सहकारिता मंत्री शिवभानु सोलंकी कभी विद्याचरण शुक्ल के खासमखास थे और विद्या भैया के बल पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अर्जुन सिंह की खिलाफत करते हुए दावा जताया था। उनके संबंध विद्याचरण से शिथिल भले ही हुए हों, मगर टूटे कतई नहीं हैं।

प्रदेश में अपनी इस लंबी-चौड़ी राजनीतिक बिरादरी के रहते हुए स्वाभाविक है कि श्री शुक्ल को यह उम्मीद रही होगी कि उनके खिलाफ आलाकमान की कार्रवाई की स्थिति में उनके राजनीतिक कुनबे के सदस्य बगावत का परचम लहरा देंगे, मगर इससे श्री शुक्ल को आघात ही लगा होगा, जब उनके लोगों ने उनका साथ छोड़ कर, प्रधानमंत्री राजीव गांधी में अटूट आस्था से ओतप्रोत बयान देने शुरू कर दिये।

शिविर त्याग: विद्याचरण शुक्ल के शिविर का त्याग करने वालों में अग्रणी और अव्वल रहे, रायपुर में कसडोल से निर्वाचित, वोरा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री डां कन्हैया लाल शर्मा। डा० शर्मा ने न केवल श्री शुक्ल के खिलाफ बयान दिया, वरन प्रधानमंत्री के प्रति अपनी निष्ठा पर मोहर लगाने के प्रयोजन से अपने प्रभार के जिलों—रायपुर, बैतूल, बालाघाट और होशंगाबाद के विधायकों की मुख्यमंत्री श्री वोरा के सामने परेड भी करा दी। अगले दिन 'माया' से चर्चा में उन्होंने कहा—"जो कुछ राजीवजी ने किया, उसे मेरा पूरा समर्थन है। मैं पार्टी के प्रति वफादार था, हूं और आगे भी रहूंगा। जहां तक श्री शुक्ल के निष्कासन से कांग्रेस पर प्रभाव पड़ने की बात है, मुझे आशा है कि पार्टी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।" जन शक्ति नियोजन और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री और प्रख्यात गीतकार विट्ठल भाई पटेल अतीत में विद्या भैया के प्रति

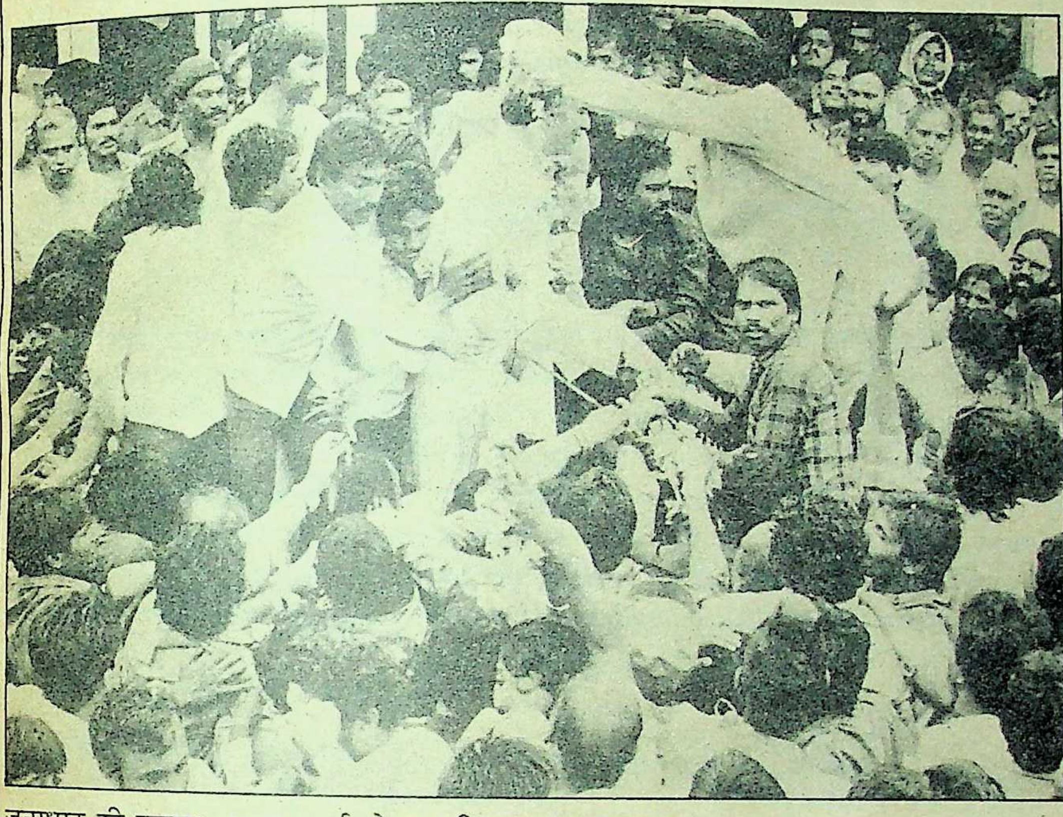

जनाधार की तलाश: माना हवाईअड्डे पर श्री शुक्ल का स्वागत

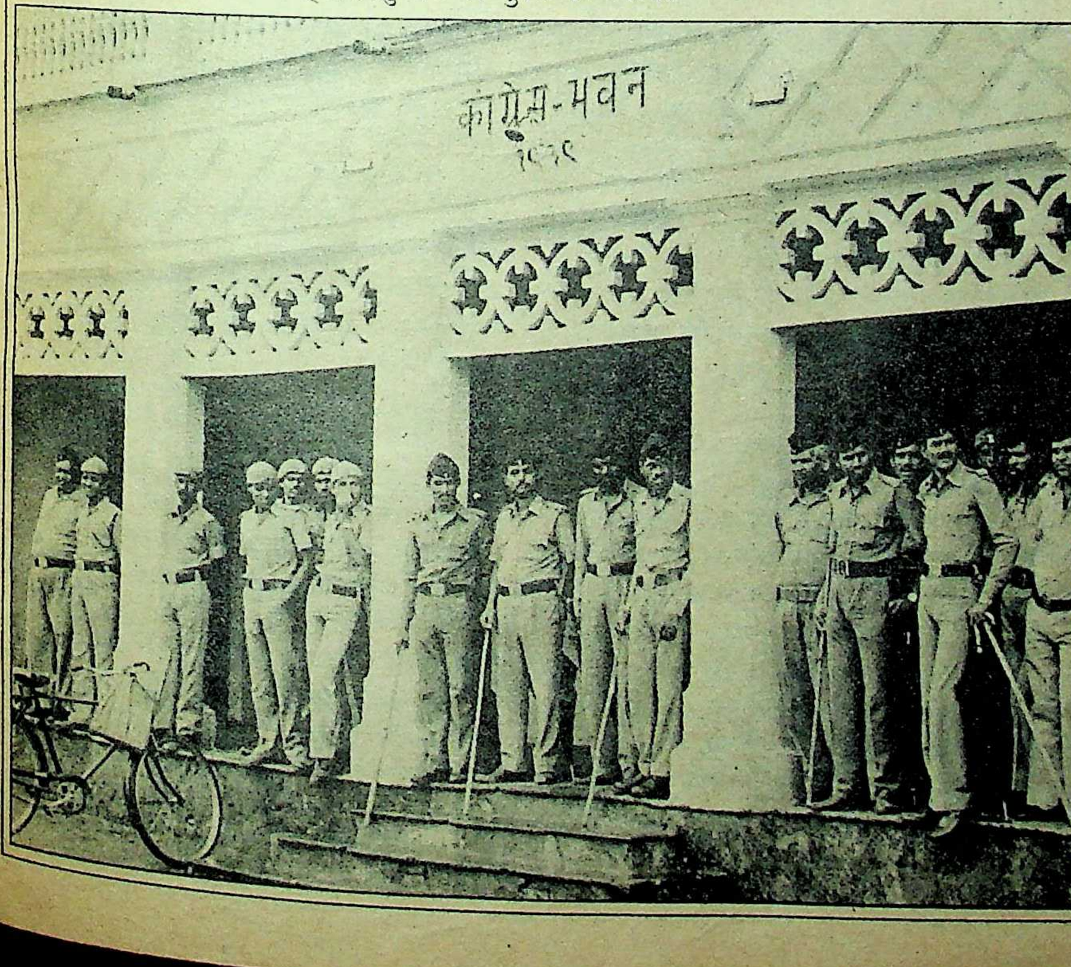

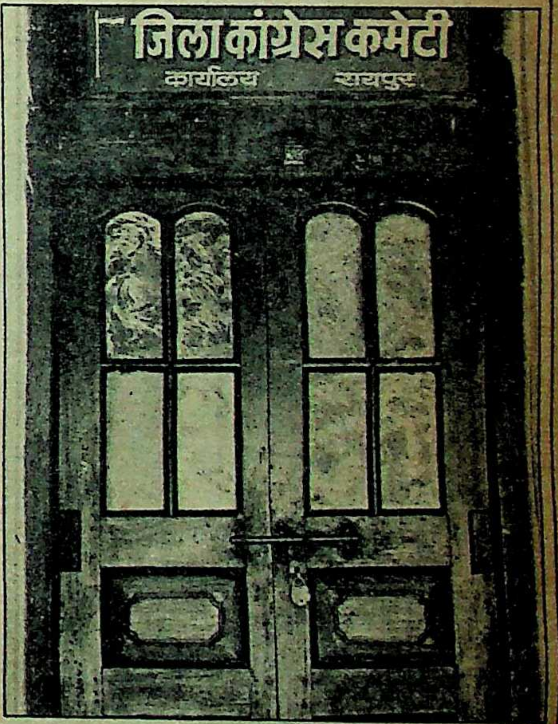

तालाबंदी और पुलिस: कांग्रेस के दफ्तर की हालत

अपनी निष्ठा कई बार व्यक्त कर चुके हैं। उनसे जब 'माया' ने संपर्क साधा, तो उन्होंने कहा—"१९६९-७० में और फिर १९७७ में जब पार्टी पर संकट आया और पार्टी बंटी, तब हमने पार्टी का साथ दिया। आज भी हम पार्टी के साथ हैं?" इसी क्रम में 'माया' ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री चित्रकांत जायसवाल से अनेक बार संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। (२२ जुलाई को तीनों मंत्रियों—डा० शर्मा, श्री पटेल और श्री जायसवाल ने बयान जारी कर कहा कि संस्था व सिद्धांत व्यक्ति से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं।) इस बयान पर लगे हाथों पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने भी हस्ताक्षर किये, ताकि भ्रम-निवारण हो और सनद रहे तथा वक्त पर काम आये।

भोपाल से निर्वाचित सांसद कृष्ण नारायण प्रधान विद्याचरण के बड़े भाई श्यामाचरण शुक्ल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 'माया' से वार्तालाप में कहा-, "मेरी राय में वी०सी० एक डेढ़ साल से राजीव गांधी और कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बना रहे थे जो कतई उचित नहीं था। उन्हें निष्कासित करने से आम कांग्रेसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" श्री प्रधान ने वी०सी० शुक्ल व उनके साथियों पर शायराना अंदाज में टिप्पणी की— "ये लोग उस चांद की तरह हैं जो यह गलतफहमी पाल लेता है कि वह खुद रोशन है।" इसी क्रम में स्थानीय शासन मंत्री तनवंत सिंह कीर ने 'माया' से कहा, "मुझे विद्याचरण शुक्ल की संदिग्ध गतिविधियों का आभास तभी हो गया था, जब उन्होंने पूर्व सांसद शिवकुमार सिंह के आमंत्रण पर बुरहानपुर की यात्रा की थी।" प्रदेश की राजनीति में श्री कीर श्री शुक्ल के साथ कभी नहीं रहे, मगर रायपुर से निर्वाचित सांसद केयूर भूषण को शुक्ल बंधुओं, विशेषकर श्यामाचरण शुक्ल का वफादार माना जाता रहा है। उन्होंने न केवल विद्या भैया के बारे में तीखा आलोचनात्मक बयान दिया, बल्कि विद्या भैया को यह सलाह देने से भी नहीं चूके कि श्री शुक्ल को अपने

साक्षात्कार/विद्याचरण शुक्ल

बिना नेतृत्व परिवर्तन के कांग्रेस को बचाना संभव नहीं

प्रदेश की राजनीति के एक वक्त के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल निष्कासन के बाद इन दिनों अलग-थलग और अकेले पड़ गये हैं। प्रदेश इंका के कोषाध्यक्ष अशोक राव, पूर्व विधायक तरुण चटर्जी के अलावा उपकृत युवा नेताओं-राजेंद्र तिवारी, सुभाष धुप्पड़, संतोष अग्रवाल, संतोष शुक्ला, विधान मिश्रा और कार्यकर्ताओं के एक समूह को छोड़ दें, तो विद्या भैया के सिपाही होने का दम भरनेवाले ओहदेदार सिपहसालारों ने श्री शुक्ल से मुंह मोड़ लिया है। सीकरी की भूलभुलैया में अंततोगत्वा उलझ गये संत कवि पवन दीवान का कहना है कि श्यामाचरण और विद्याचरण छत्तीसगढ़ के लिये 'राहु-केतु' हैं। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने 'माया' से कहा— "इंदिरा कांग्रेस को 'नकली कांग्रेस' कहने का विद्याचरण को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कल वह इसी कांग्रेस के टिकट पर संसद के लिये चुने गये थे। उन्हें चाहिए कि इस्तीफा दें और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें।" जहां तक विद्याचरण शुक्ल का प्रश्न है, वह अकेले या वक्त की मार खाये भले ही हों, लेकिन उनका दर्प और उनके तेवर बरकरार हैं। इधर उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ से हटाने की भी मांग की जा रही है। 'माया' संवाददाता की उनसे मुलाकात १९ जुलाई को हुई, जब उन्हें अपने गृहनगर आये कुछ ही घंटे बीते थे। प्रस्तुत है, रायपुर में बूढ़ापारा में श्री शुक्ल से उनके आवास पर हुई बातचीत के अंश:

अपनी झूठ बोलने की प्रवृत्ति, अनुभवहीनता और किसी आदर्शवाद से न जुड़े होने के कारण या कहना चाहिए कि राजनीतिक चिंतन के अभाव में, राजीव सर्वथा असफल प्रधानमंत्री रहे हैं।

माया: कांग्रेस-इ से अपने निष्कासन के बारे में आप क्या कहेंगे?

शुक्ल: इसे मैं निष्कासन नहीं मानता। कांग्रेस का वर्तमान पूरा ढांचा एक कृत्रिम आधार पर निर्मित है। यह नामजद ढांचा है, जो मुझ सरीखे विधिवत निर्वाचित लोगों को निकाल नहीं सकता। वैसे भी कोई ऐसा कार्य जीवनपर्यंत मैंने नहीं किया, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा हो। यह बात सब जानते हैं कि १९७७ से ८० तक मैंने, कितने खतरे मोल लेकर, किस ढंग से कांग्रेस और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सेवा की।

माया: क्या आपको यह लगता है कि आपको निकाले जाने के पीछे किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र है?

शुक्ल: इसमें षड्यंत्र नहीं, परंतु भय की मानसिकता है। भय और हीनता की भावना से ग्रस्त होकर परंपरागत व निष्ठावान कांग्रेसियों की निरंतर उपेक्षा राजीव गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से हो रही है। एक-न-एक किसी बिंदु पर कांग्रेस की रक्षा के लिए कार्रवाई करना आवश्यक था। हम लोगों ने यह कहा था कि हम लोग विभिन्न मुद्दों को पार्टी के विभिन्न मंचों से दलीय अनुशासन के तहत उठायेंगे। लगता है इससे भयभीत होकर हम लोगों के खिलाफ कदम उठाया गया और उनके खिलाफ भी उठाया जायेगा, जो यह काम करेंगे।

माया: प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में आपकी क्या राय है?

शुक्ल: राजीव हर क्षेत्र में असफल रहे हैं। अपनी झूठ बोलने की प्रवृत्ति, अनुभवहीनता और किसी आदर्शवाद से न जुड़े होने के कारण या कहना चाहिए कि राजनीतिक चिंतन के अभाव में, राजीव सर्वथा असफल प्रधानमंत्री रहे हैं। ढाई साल हम लोग इसी आशा में बैठे रहे कि राजीव सुधरेंगे, सबक सीखेंगे, जिसका कि वायदा वह व्यक्तिगत चर्चाओं में व कभी-कभी सार्वजनिक तौर पर करते रहे। इसीलिए हम लोग—आम कांग्रेसी—उन्हें 'बेनिफिट ऑफ डाउट'—(संदेह का लाभ) देते रहे।

माया: यानी आप लोगों को उन पर संदेह था?

शुक्ल: हां। संदेह था, पर लाभ उन्हें मिलता रहा, पर इनके कार्यकाल में इनके कार्यों के आधार पर हर चुनाव में भारतीय जनता ने इन्हें बारंबार ठुकराया है, जबकि इस जनता की कांग्रेस के प्रति आस्था में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। अंततः, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिना नेतृत्व-परिवर्तन के कांग्रेस को बचाना संभव नहीं है।

माया: लेकिन नेतृत्व-परिवर्तन की मांग करना क्या अनुशासनहीनता नहीं है?

शुक्ल: नेतृत्व-परिवर्तन करने का प्रयास करने का हरेक पार्टी सदस्य का स्वयंसिद्ध हक है व हर पार्टी में, विशेषकर कांग्रेस में, यह परंपरा रही है।

कार्यों पर विचार-मंथन कर पश्चाताप करना चाहिए। रायपुर में कांग्रेस भवन की बैठक में भी केयूर भूषण काफी मुखर रहे। इस बैठक में मध्यप्रदेश युवा इंका के अध्यक्ष व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद थे और उन्होंने पार्टी नेतृत्व, सिद्धांतों और अनुशासन की दुहाई देते हुए श्री शुक्ल को आड़े हाथों लिया। प्रदेश इंका अध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में जारी अपने बयान में कहा कि विद्याचरण शुक्ल इंका की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे। उनका ध्येय पद से चिपके रहना है। श्री शुक्ल के बयान से जाहिर है कि वह एक षड्यंत्र में लिप्त हैं। राजीव गांधी में आस्था व्यक्त करते हुए इससे मिलता-जुलता वक्तव्य पूर्व-सांसद गुफराने आजम ने भी दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शुक्ल के निष्कासन ने अनेक नेताओं को अपनी चुप्पी तोड़ने का अवसर सुलभ कर दिया। मध्य प्रदेश इंका विधायक दल की महासचिव कुमारी विमला वर्मा ने श्री शुक्ल के इस आशय के बयान पर कड़ी आपत्ति की कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी नकली कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि यह कथन नेहरू परिवार और श्रीमती इंदिरा गांधी का अपमान है। लक्ष्मीनारायण इंदूरिया जैसे नेताओं की आज जो भी राजनीतिक हस्ती है, वह मूलतः श्री शुक्ल की देन है। बयानबाजी की झोंक में इंदूरिया व अनेक नेताओं ने बारंबार बयानबाजी की। रायपुर में खल्लारी से निर्वाचित श्री इंदूरिया ने कहा कि सांसद विद्याचरण शुक्ल कुंठा व हताशा से ग्रस्त हैं। उनका प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना हास्यास्पद है। इसी क्रम में बालकवि बैरागी, दिलीप सिंह भूरिया, अरविन्द नेताम, शिवेंद्र बहादुर आदि सांसदों ने श्री शुक्ल के निष्कासन का स्वागत किया।

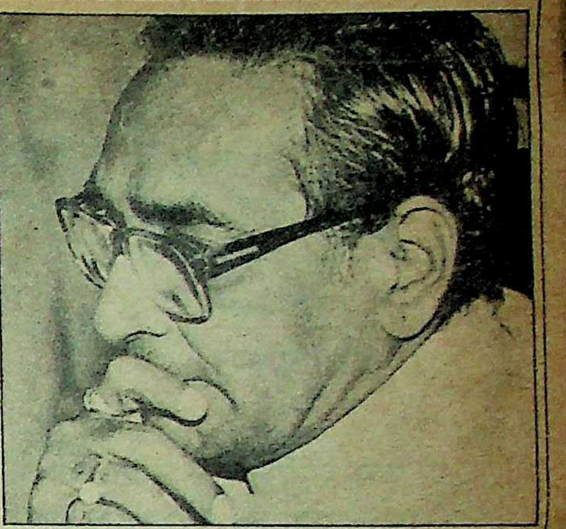
चिंतित : मोतीलाल वोरा

रायपुर में : रायपुर श्री शुक्ल का गृह नगर है और उनकी गतिविधियों का केंद्र भी। उनके पिता स्व० पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आम कांग्रेसी व मध्य प्रदेशवासी गौरव, सम्मान व श्रद्धा से लेते हैं। उनके अग्रज श्यामाचरण शुक्ल में राजनीतिक तौर पर आस्था रखनेवालों की भी मध्यप्रदेश में कमी नहीं है। संख्या भले ही कम हो, मगर आज भी मध्यप्रदेश में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, जहां लोग आपसी बातचीत में शुक्ल-परिवार की कांग्रेस में निष्ठा, विद्याचरण के अभिजात्य दर्प और हर कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं का साथ देने की प्रवृति की सराहना न करते हों। छत्तीसगढ़ में तो राजनीतिक मौसम व समीकरण में कितनी भी फेरबदल क्यों न हो, राजनीतिक असहमति के बावजूद विद्या भैया की इस आशय की विरुदावलि गानेवालों की कमी नहीं है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जितना किया, उतना किसी और नेता ने नहीं।

श्री शुक्ल के निष्कासन का रायपुर में सर्वाधिक असर पड़ना स्वाभाविक था। श्री शुक्ल के निष्कासन से शर्मा बंधुओं—अपेक्स हाउसिंग के अध्यक्ष व विधायक सत्यनारायण शर्मा और म०प्र० भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष व रायपुर जिला इंका कमेटी (ग्रामीण) के उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा—की तो मनचाही मुराद पूरी हो गयी। शर्मा-बंधुओं का कहना था कि श्री शुक्ल का निष्कासन तो चार साल पहले ही हो जाना चाहिए था। शर्मा-बंधुओं, रायपुर शहर कांग्रेस—इ कमेटी के अध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवी, उपाध्यक्ष लक्ष्मण सत्पथी, रामगुलाम सिंह ठाकुर, नरेंद्र मिश्रा आदि ने श्री शुक्ल के निष्कासन का स्वागत किया। जिला कांग्रेस-इ कमेटी ने १८ जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया कि जो भी श्री शुक्ल को सहयोग देगा, उसे दल से निकाल दिया जायेगा। इस प्रस्ताव का असर तो हुआ, मगर अगले रोज उन्हें ग्रामीण जिला कांग्रेस से सुभाष धुप्पड़,

इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, पर यह पहला मौका है कि इस कारण से कांग्रेस के निष्ठावान सदस्यों को निष्कासित किया गया है। जब तक मतभेद न हों, तब तक किसी भी राजनीतिक दल में वह स्वस्थ राजनीतिक व वैचारिक प्रक्रिया नहीं होती, जिसके आधार पर पार्टी का कार्य चलता है। इस राजनीतिक मतभेद को विद्रोह की संज्ञा दी जाये, तो यह न केवल अनुचित है, अपितु कांग्रेस की परंपरा व कांग्रेस के स्वास्थ्य के लिए घातक है।

माया : हरियाणा में कांग्रेस की शर्मनाक पराजय से क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी-प्रदेशों में कांग्रेस के पराभूत होने के सिलसिले की शुरुआत हो गयी है?

शुक्ल : हरियाणा में जिन कारणों से कांग्रेस की हार हुई है, यदि उन्हें दूर न किया गया, तो कमोबेश हर प्रदेश में व केंद्र में इसी प्रकार की हार का सामना करना पड़ेगा।

माया : अमिताभ बच्चन पर लगे आरोपों और फिर उनके इस्तीफे के बारे में आपकी क्या राय है?

शुक्ल : अमिताभ पर लगे आरोपों के बारे में अरुण शौरी ने प्रमाण व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। उसके आधार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग को तो 'प्राइमा फेसी' पता लगाने के लिये बिठाया जाता है। जहां, प्राइमा फेसी दिख रहा हो, वहां आयोग बिठाना अपने दोस्त को बचाने की निरर्थक कोशिश मानी जायेगी। इसी तरह इस्तीफा देने से यह दोष मुक्ति नहीं पा जाता। मेरा कहना है कि विभिन्न सौदों—फेयरफैक्स, पनडुब्बी, बोफोर्स—व अन्य मामलों की जांच संसदीय समिति को सौंपनी चाहिए और सुनवाई सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए।

माया : आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हैं। क्या यह बात सही है?

शुक्ल : ऐसी अभिलाषा रखना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। परंतु मैंने ऐसी न तो कोई इच्छा रखी और न ही जाहिर की, क्योंकि मैं इसे दृढ़ता से मानता हूं कि केवल सेवा, चरित्र और देशभक्ति के आधार पर बड़े राजनीतिक पद मिल सकते व टिक सकते हैं।

माया : पिछले दिनों आपने राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह से अनेक मुलाकातें कीं और इनके तरह-तरह के अर्थ भी लगाये गये। इन मुलाकातों का क्या कोई विशेष प्रयोजन था?

शुक्ल : मेरी मुलाकात ज्ञानीजी से निरंतर होती रही है। एक तरह से जब से वह राष्ट्रपति बने हैं, तब से। और ज्ञानीजी की कृपा रही कि उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर हमेशा मुझसे बहुत सी चर्चाएं कीं। इसलिए इन पिछली कुछ महीनों की मुलाकातों का अलग से कोई महत्व नहीं है।

माया : हाल में आप कमलापतिजी से भी मिले हैं...

शुक्ल : कमलापतिजी से समय-समय पर चर्चा हुई है, होती रहती है।

माया : आपके बयानों को कुछ लोगों ने सी०आई०ए० से जोड़ा है...

शुक्ल : यह हास्यास्पद है। इसके अलावा और क्या कहूं।

माया : आपके खिलाफ मंत्रियों व मुख्यमंत्री से लेकर छुटभैये नेताओं ने तरह-तरह के बयान दिये हैं। इन पर आपकी प्रतिक्रिया?

शुक्ल : ये सब प्रोफार्मा-बयान हैं। पहले तो ये लोग बयान देते हैं, फिर मिलकर व्यक्तिगत चर्चा में माफी मांगते हैं।

माया : अब आपने आगे की क्या रणनीति तय की है?

शुक्ल : कांग्रेस की संस्कृति व उसकी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए उन लोगों को हटाना जरूरी है जो भ्रष्टाचार व अनाचार को प्रश्रय दे रहे हैं। मैं अपने को पूर्णरूपेण कांग्रेसी मानता हूं और हम सब अब मिलकर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी मेहनत करेंगे।

माया : क्या आप अपने अभियान में विपक्षी दलों का सहयोग लेंगे?

शुक्ल : इसमें विपक्षी दलों से कोई सरोकार नहीं रहेगा। यह हमारा आंतरिक मामला है। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जब भी ऐसे संकट आये हैं, कांग्रेसजनों ने ही ऐसे संकटों से कांग्रेस को उबारा है। इसलिए इस कार्य में दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि हम सब विभाजन के सर्वथा विरुद्ध हैं।

कन्हैया लाल शर्मा

> "जो कुछ राजीवजी ने किया, उसे मेरा पूरा समर्थन है। मैं पार्टी के प्रति वफ़ादार था, हूं और आगे भी रहूंगा।"

राजेंद्र तिवारी, के०के० धांद, राजेंद्र अग्रवाल और शहर जिला इंका से पूर्व विधायक व महापौर तरुण चटर्जी, बलवीर जुनेजा, नरेंद्र तिवारी, विधान मिश्रा, वासु चक्रवर्ती, गोविंद शर्मा, वकील पहलवान और अब्दुल रहीम धांधू को पार्टी से निकालना पड़ा। उधर श्री शुक्ल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महासमुंद में १७ व १८ जुलाई को कतिपय पदाधिकारियों समेत ४२ कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र दे दिया। दूर पथरिया में नगर युवा इंका के अध्यक्ष संतोष दुबे, उपाध्यक्ष श्री भारद्वाज और महामंत्री द्वारका शर्मा समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। १९ जुलाई को एक दिलचस्प बात यह हुई कि यह भनक पड़ते ही कि विद्या भैया के समर्थक उनको लेकर कांग्रेस भवन जाने की योजना बना रहे हैं, कांग्रेस भवन में ताले जड़ दिये गये और वहां पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी गयी।

आगे के आसार : हालांकि, मंत्रियों, विधायकों और प्रदेश इंका के पदाधिकारियों में से किसी ने भी श्री शुक्ल के समर्थन में खुलकर सामने आने और इस्तीफा देने का साहस नहीं दिखाया है, लेकिन यह माना रहा है कि दो मंत्री-चित्रकांत व विट्ठल भाई देरसबेर श्री शुक्ल के साथ आ सकते हैं। इस संभावना को इससे बल मिलता है कि श्री जायसवाल ने प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह के निर्देश पर प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त नहीं की और श्री पटेल २३ जुलाई को भोपाल में प्रदेश इंका विधायक दल की कार्यकारिणी की उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिसमें चौकड़ी के इंका से निष्कासन का स्वागत किया गया। आश्चर्यजनक तौर पर, धमतरी की विधायक जयाबेन ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। श्री शुक्ल यदि छत्तीसगढ़ में हवा का रुख अपने पक्ष में बनाये रखने में कामयाब होते हैं, तो कुछेक विधायक भी इंका के खूंटे से पगहा तुड़ाकर अपने नेता के साथ आ सकते हैं। प्रदेश इंका के जिस एकमात्र नेता ने अभी तक अपने नेता के साथ खड़े होने का साहस प्रदर्शित किया है, वह हैं प्रदेश इंका के कोषाध्यक्ष व बिलासपुर के प्रथम महापौर अशोक राव। श्री राव ने सभी पदों से इस्तीफा देकर श्री शुक्ल में आस्था व्यक्त की है। अपने समर्थकों की इस्तीफे की अटकलों पर श्री शुक्ल ने अपनी ओर से यह कह कर परदा डालने की कोशिश की है कि उन्होंने अभी अपने समर्थकों को इस्तीफा देने से मना कर दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह उनकी अपनी कमजोरी को ढंकने की चाल है, तो कुछ लोगों का कयास है कि श्री शुक्ल अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खेलना चाहते हैं।

जहां तक जाहिर तौर पर श्री शुक्ल के समर्थकों का प्रश्न है, आज की तारीख में उनमें अनुभवी व प्रभावी नेताओं के बजाय युवा कार्यकर्ताओं की भरमार है। ये कार्यकर्ता अपने नेता के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष प्रमोद दुबे अपने सहयोगी छात्र नेताओं के साथ खुलेआम विद्याचरण के साथ हैं। शुक्ल समर्थकों के मिजाज का पता इससे चलता है कि इंका सांसद केयूर भूषण २१ जुलाई को जब इंका कार्यकर्ताओं को संबोधित करने भाटापारा पहुंचे, तो शुक्ल-समर्थकों ने 'केयूर भूषण वापस जाओ' के नारे लगाये। अंततः क्षुब्ध सांसद महोदय उत्तेजित कार्यकर्ताओं के बीच से पुलिस की मदद से ही बाहर निकल सके। बाद में जब वह बलोदाबाजार जा रहे थे, तब भी उनकी कार कुछ युवकों ने रोकी। रायपुर के एक नेता ने 'माया' से कहा कि मध्य प्रदेश के राजनीतिज्ञ संभवतः वह प्रसंग भूले नहीं होंगे, जब स्व० रविशंकर शुक्ल के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप के कारण रायपुर में युवकों ने अजीज कुरैशी (अब सतना से सांसद) की दुर्गति की थी और श्री कुरैशी को दुम दबाकर भागना पड़ा था। उक्त नेता ने यह भय भी व्यक्त किया कि शुक्ल-बंधुओं के खिलाफ आज जो लोग बढ़चढ़ कर बयान दे रहे हैं, उन्हें कल युवकों के रोष और आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।

विद्याचरण शुक्ल को छत्तीसगढ़ में अपनी लड़ाई अकेले भले ही लड़नी पड़े, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी और उनकी लड़ाई की सफलता-असफलता सहयोगी तिकड़ी यानी वी०पी० सिंह, आरिफ मोहम्मद खां और अरुण नेहरू की सफलता-असफलता से जुड़ी हुई है। किशोरी लाल शुक्ल जैसे वयोवृद्ध कांग्रेसी यह मानते हैं कि श्री शुक्ल का इंका से निष्कासन दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे अंततोगत्वा कांग्रेस की ही हानि होगी। कांग्रेस-इ के पास छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और विधायकों की फौज और लवाजमा जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि पार्टी के पास विद्याचरण शुक्ल के कद का एक भी नेता नहीं है। श्री शुक्ल ने अपने खिलाफ बयान देनेवालों को आड़े हाथों लेते हुए 'माया' से चर्चा में कहा, "लोग मेरे खिलाफ दिन में तो बयान देते हैं, मगर रात में आकर पैर छूकर माफी मांगते हैं।" श्री शुक्ल ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर 'माया' संवाददाता ने पाया कि एक दिन पूर्व पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करनेवाले पूर्व विधायक लक्ष्मणसत्पयी १९ जुलाई की शाम को विद्या भैया के घर में मौजूद थे। मध्य प्रदेश में कुछेक सांसद ऐसे भी हैं, जिन्हें टिकट दिलाने में अरुण नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे सांसदों में लोकसभा सदस्य प्रतापभानु शर्मा, कर्नल अजय मुश्रान, गार्गी शंकर मिश्रा और राज्य सभा के सदस्य चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी का समावेश है। राज्य सभा चुनावों के मौके पर जगतपाल सिंह और ललित श्रीवास्तव को टिकट मिलने के आसार थे, किंतु अरुण नेहरू की कृपा से ऐन वक्त पर श्री श्रीवास्तव की जगह श्री त्रिपाठी को टिकट मिल गया। उक्त सांसदों में श्री शर्मा ने ही अभी तक बारंबार और पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री में आस्था और निष्ठा का इजहार किया है और शेष तीनों चुप्पी साधे हुए हैं।

के०एन० प्रधान

चित्रकांत जायसवाल

विट्ठलभाई पटेल

> "१९६९-७० में और फिर १९७७ में जब पार्टी पर संकट आया और पार्टी बंटी, तब हमने पार्टी का साथ दिया। आज भी हम पार्टी के साथ हैं।"

वी०पी० सिंह की मध्यप्रदेश में कोई लॉबी नहीं है, लेकिन उनकी अबाध लोकप्रियता असंदिग्ध है। कोई आश्चर्य नहीं यदि रायपुर से जन जागरण अभियान प्रारंभ करने की विश्वनाथ प्रताप सिंह की घोषणा से मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की नींद हराम हो गयी हो। आरिफ मोहम्मद खां का आगमन भी कतिपय अल्पसंख्यक नेताओं को श्री शुक्ल के पक्ष में गोलबंद कर सकता है। चूंकि, श्री शुक्ल केंद्र में अर्से तक छतीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अतः जानकार सूत्रों के मुताबिक जनता में यह प्रचारित करने की योजना बनायी जा रही है कि दिल्ली-दरबार ने छतीसगढ़ की उपेक्षा व अवमानना की है। योजना है कि उक्त भावना उभार कर श्री शुक्ल को 'छतीसगढ़ के देवीलाल' का चोगा पहनाया जाये। यदि ऐसा होता है, तो जाहिर है कि इंका नेताओं, विशेषकर मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। श्री शुक्ल की मजबूरी यह है कि श्री शुक्ल के पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है। उन्हें अपने अस्तित्व व सम्मान की लड़ाई लड़नी है। उनके इंका से निष्कासन से प्रदेश की राजनीति पर तात्कालिक असर यह पड़ा है कि मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के लिए पद पर टिके रहने के लिए अब कुंवर साहब (अर्जुन सिंह) का दामन थामना अनिवार्य हो गया है।

छाया : आर०सी० साहू, गोकुल सोनी

रामू दादा की सूझ-बूझ

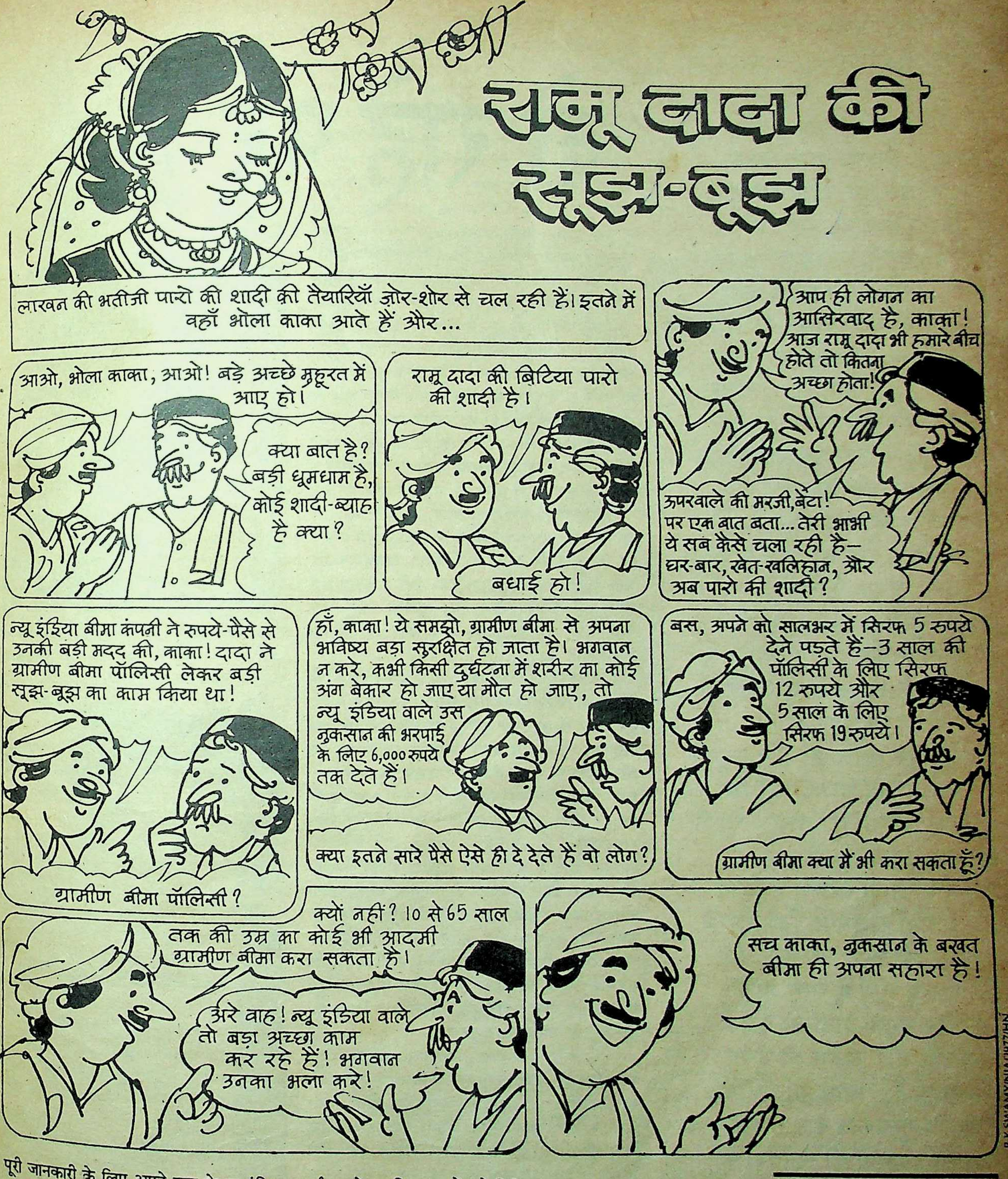
लाखन की भतीजी पारो की शादी की तैयारियाँ ज़ोर-शोर से चल रही हैं। इतने में वहाँ भोला काका आते हैं और...
आओ, भोला काका, आओ! बड़े अच्छे मुहूरत में आए हो।
क्या बात है? बड़ी धूमधाम है, कोई शादी-ब्याह है क्या?
रामू दादा की बिटिया पारो की शादी है।
बधाई हो!
आप ही लोगन का आसिरवाद है, काका! आज रामू दादा भी हमारे बीच होते तो कितना अच्छा होता!
ऊपरवाले की मरजी, बेटा! पर एक बात बता... तेरी भाभी ये सब कैसे चला रही है— घर-बार, खेत-खलिहान, और अब पारो की शादी?
न्यू इंडिया बीमा कंपनी ने रुपये-पैसे से उनकी बड़ी मदद की, काका! दादा ने ग्रामीण बीमा पॉलिसी लेकर बड़ी सूझ-बूझ का काम किया था!
ग्रामीण बीमा पॉलिसी?
हाँ, काका! ये समझो, ग्रामीण बीमा से अपना भविष्य बड़ा सुरक्षित हो जाता है। भगवान न करे, कभी किसी दुर्घटना में शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए या मौत हो जाए, तो न्यू इंडिया वाले उस नुकसान की भरपाई के लिए 6,000 रुपये तक देते हैं।
क्या इतने सारे पैसे ऐसे ही दे देते हैं वो लोग?
बस, अपने को सालभर में सिरफ 5 रुपये देने पड़ते हैं—3 साल की पॉलिसी के लिए सिरफ 12 रुपये और 5 साल के लिए सिरफ 19 रुपये।
ग्रामीण बीमा क्या मैं भी करा सकता हूँ?
क्यों नहीं? 10 से 65 साल तक की उम्र का कोई भी आदमी ग्रामीण बीमा करा सकता है।
अरे वाह! न्यू इंडिया वाले तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं! भगवान उनका भला करे!
सच काका, नुकसान के बखत बीमा ही अपना सहारा है!
R K SWAMY/NIA/2977/HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इंडिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

न्यू इंडिया एश्योरेंस

(जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की एक सहायक कंपनी)

बीमा — नुकसान में आपका सहारा!

ऐन मारो ने अपनी पुस्तक 'हाईनेस' में भारतीय रियासतों के गौरवमय अतीत का चित्रण और उन परिस्थितियों का विशद वर्णन किया है, जिनकी वजह से इन रियासतों का भारतीय गणराज्य में विलय हुआ था और देश के सारे रियासती घराने भारत के आम नागरिक बन गये थे। जहां तक ग्वालियर रियासत का सवाल है, उसे पांच विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनमें २१ तोपों की सलामी भी शामिल थी। राजमाता और उनके पुत्र के लिए उनकी रियासत का विलय, अन्य रियासतों के मुकाबले कहीं अधिक सहज और सरल ढंग से हुआ था। ऐन मारो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजमाता के पुत्र और उत्तराधिकारी माधवराज सिंधिया ने अपने शाही अतीत के प्रति आदर और गौरव रखते हुए अपनी अत्याधुनिक व्यक्ति की छवि बनायी है। माधव राव का कहना है कि उनका पुत्र ज्योतिरादित्य भारत के आम नागरिक 'श्री सिंधिया' के रूप में ही जाना जायेगा। उनकी ६८ वर्षीया राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी सफेद परिधान और विशिष्ट गांभीर्य के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता और कांग्रेस की मुखर आलोचक हैं। 'माया' प्रतिनिधि से विशेष मुलाकात में वह जहां रियासती जमाने की स्मृतियों को ताजा करती रहीं, वहीं उन्होने राजघराने के अन्य सदस्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की :

विजयाराजे सिंधिया

दो राहे पर

जब राजमाता ग्वालियर विजयाराजे सिंधिया हमारा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ीं, तो उनकी शाही चाल और सौम्य मुद्रा के अतिरिक्त ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जो उनके भूतपूर्व महारानी होने का संकेत देती हो। राजमाता मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि की हैं और ग्वालियर राजघराने के शाही तौर-तरीके कुशलतापूर्वक अपनाने के बावजूद अपनी मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। जब उन्होंने पहली बार राजघराने के प्रांगण में कदम रखा था, तो वह बेहद घबड़ाई हुई थीं। उन दिनों का स्मरण करते हुए राजमाता ने बताया, "जहां से मैं आयी थी, वहां की और यहां की परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर था। उन दिनों मैं यही प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे आपे में रखे।" दूसरी ओर माधवराज सिंधिया, राजघराने और आम आदमी—दोनों की भूमिका बड़ी कुशलतापूर्वक निभाते हैं। उनके अनुसार यह भूमिका सहज और स्वाभाविक नहीं थी, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी है।

माधवराज सिंधिया का जन्म न केवल राजघराने में हुआ था, बल्कि दो कन्याओं के बाद पैदा होने के कारण पूरे राज्य में अभूतपूर्व खुशियां बनायी गयी थीं। उन दिनों की स्मृतियों में खोयी राजमाता स्वाभाविक हर्ष और आतुरता से बताती हैं, "राजाजी (राजगोपालाचार्य) उस समय ग्वालियर में थे, उन्होंने कहा था कि मैंने तो, ऐसे (रामजन्म पर हुए) समारोहों का वर्णन रामायण में ही पढ़ा था।" तस्कनी और पैलेडियन स्थापत्य शैली से बने १९वीं शताब्दी के जय विलास पैलेस और उसके पारदर्शी झाड़फानूस, अनंत शिल्प-कलाकृतियां, जरीदार चमकते परदे और नौकरों की लंबी-चौड़ी फौज के बीच माधवराज की ऐसी शिक्षा-दीक्षा संभव नहीं थी जो उन्हें आज के दिनों के लिए तैयार कर सकती। यह तो भारत और इंग्लैण्ड के छात्रावासों में रहते हुए प्राप्त उदार और लोकतांत्रिक शिक्षा थी, जिसने उन्हें समयानुसार ढाला।

परदे के खिलाफ मोर्चा : बहरहाल, सीखने और रूढ़ियों को तोड़ने पर तो मूल रूप से विजयाराजे सिंधिया का ही विशेषाधिकार रहा है। उन्हें पहला मोर्चा 'परदा प्रथा' से लेना पड़ा। उनकी शादी 'चट मंगनी, पट ब्याह' की शैली में हुई थी कि उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर की इस किशोरी को इतना वक्त ही नहीं मिला कि वह राजघराने के तौर-तरीके सीख सकती। उस समय तो स्वाभाविक रूप से उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, जब उन्होंने देखा कि दुल्हन की अगवानी के लिए केवल महिलाएं ही आयी थीं और सारे रास्ते भर दोनों ओर परदों की दीवार बना दी गयी थी।

अतीत का वर्तमान : महल में राजमाता सिंधिया

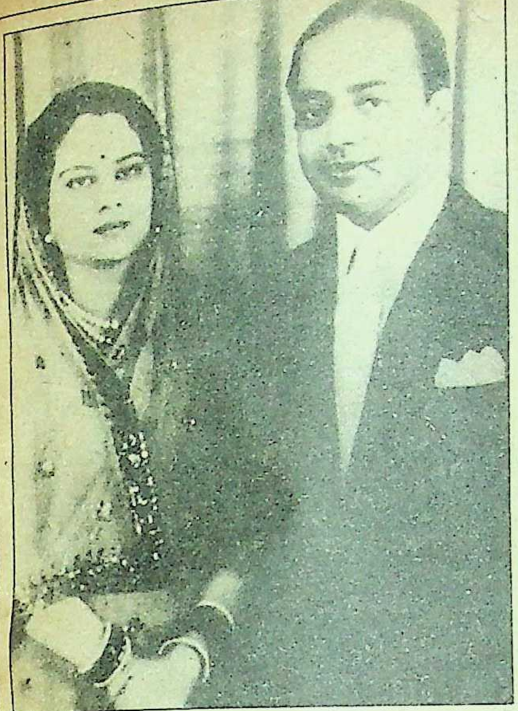

शाहीं दम्पती : स्वर्गीय महाराजा के साथ राजमाता

यहां तक कि जिस 'पैकार्ड कार' में वह आयी थीं, उस पर भी परदे टंगे थे। सर्वाधिक आश्चर्य तो उन्हें उस समय होता था, जब उनके कदमों की आहट सुनते ही पुरुष नौकर दौड़कर दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाते थे मानो स्कूल के मास्टर ने उन्हें दण्ड दिया हो। राजमाता ने बताया, "काफी दिनों बाद महाराजा ने समझाया कि ऐसा वे सम्मान प्रदर्शित करने के लिए करते हैं और इसलिए भी कि कहीं मुझसे उनका आमना-सामना न हो जाये।"

यद्यपि ग्वालियर रियासत में होनेवाले सभी सम्मेलनों व दरबारों में 'परदा प्रथा' कायम थी और महारानी सिर्फ महिलाओं के दरबार में ही हिस्सा ले सकती थीं, लेकिन उन्हें रियासत के बाहर 'परदे' से छूट मिली हुई थी। 'परदे' से वास्तविक मुक्ति तो उन्हें उस समय मिली, जब भारतीय गणराज्य में ग्वालियर रियासत के विलय के बाद सरदार पटेल ग्वालियर आये। उन्होंने इस प्रथा की निरर्थकता के बारे में राजमाता को समझाते हुए कहा था कि जनता उन्हें 'मां' मानती है, अतः अपनी संतान के सामने परदा कैसा! इस पर रियासत के कुलीन वर्ग के लोगों ने बड़ा बावेला मचाया, लेकिन महारानी ने सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने में इन आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया।

परदे से राजनीति में : परदे से निकलकर भारतीय राजनीति की उठापटक और धमाचौकड़ी में सक्रिय होना वास्तव में विजयाराजे सिंधिया के लिए एक लंबी छलांग थी। ऐसा उन्होंने अनायास, लेकिन झिझक के साथ किया था। वह खेद के साथ बतलाती हैं, "यही एक ऐसा कार्य था, जिसे मैंने महाराजा साहब से सलाह लिये बगैर किया था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थीं कि कोशिश करके भी मैं बंबई में उनसे न तो ग्वालियर से और न ही दिल्ली से संपर्क कर सकी। दिल्ली में मैं पंडित नेहरू से मिलने गयी थी। पंडितजी ने मेरे सामने इसके सिवा कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा कि मैं या महाराजा कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ें। चूंकि, महाराजा ने इनकार कर दिया था, इसलिए १९५७ में मुझे कांग्रेस-टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया।

उसके बाद फिर विजयाराजे सिंधिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह १९५७ का चुनाव भारी बहुमत से जीतीं और १९६२ में तो चुनाव-प्रचार न करने के बावजूद वह रिकार्ड मतों से विजयी रहीं। वह बताती हैं, "उन दिनों महाराजा के निधन पर एक वर्षीय शोक मनाया जा रहा था, इस कारण मैं १९६२ का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन पंडित नेहरू ने इसके लिए न केवल जोर डाला, बल्कि उन्होंने स्वयं चुनाव-प्रचार-अभियान का उद्घाटन भी कर दिया। चुनाव-प्रचार का कार्य बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने संभाला था।" लेकिन कांग्रेस से उनका 'हनीमून' ज्यादा दिन नहीं चला। मध्य प्रदेश में डी०पी० मिश्रा के पुलिस-राज के जुल्म जोरों पर थे और वह कठपुतली की तरह इन सारे जुल्मों को असहाय-सी देख रही थीं। 'बस्तर काण्ड' (राजा भुंजदेव की हत्या) के तत्काल बाद वह कांग्रेस से अलविदा कहकर विपक्ष में शामिल हो गयीं। उनका यही एक फैसला आज तक उनके पुत्र के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लेकिन उनकी मां को इसका कोई गिला नहीं है, यह उनका वैसा ही सोचा-समझा फैसला था, जैसा कि उन्होंने राजनीति में बने रहने के लिए किया था।

दोस्त से दुश्मन : श्रीमती गांधी के साथ राजमाता (वायें कोने में)

राजमाता के जनसंघ-प्रवेश से श्रीमती गांधी का खिन्न होना स्वाभाविक था। आगे के चुनाव-परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि राजमाता ऐसी ताकत हैं, जिसको आसानी से जीतना संभव नहीं है। इससे श्रीमती गांधी की चिंता और बढ़ी। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में दलबदल कराकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी, तो फिर जवाबी वार शुरू हो गया। उन्हें अपमानित किया गया और उनके लिए पग-पग पर परेशानियां खड़ी की गयीं। जब आपातकाल की घोषणा हुई, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें और अपमानित करने के लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली के तिहाड़ जेल ले आया गया, जहां जयपुर की गायत्री देवी के साथ उन्हें चोरों, हत्यारों, और वेश्याओं के बीच रखा गया। राजमाता के अनुसार, "ऐसा इसलिए किया गया, जिससे हमारा मनोबल टूट जाये और हम उनके (श्रीमती गांधी) सामने घुटने टेक दें। बहरहाल, मैंने निश्चय कर लिया कि परेशान होकर मैं श्रीमती गांधी

आधुनिका महारानी अपनी पुत्री के साथ

माधवराव सिंधिया

जन्मजात शासक

माधवराव सिंधिया को यद्यपि इस बात का गर्व है कि वह शाही नहीं, बल्कि कृषक पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन राजशाही का प्रभामंडल उनके साथ-साथ चलता है। हाल में जब वह ग्वालियर से दिल्ली लौट रहे थे, तो उनके हस्ताक्षर (आटोग्राफ) लेने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इनमें हर उम्र की महिलाएं थीं। अभी तक तो ऐसे दृश्य किसी खद्दरधारी नेता के नहीं, बल्कि फिल्मी अभिनेता के आसपास ही दिखायी देते थे। लगता है, यह नेता (माधवराव) सर्वोत्तम अभिनेता बन गया है।

अपने गृह प्रदेश में माधवराव सिंधिया की लोकप्रियता देखते ही बनती है। वह आम आदमी के दिल को छू जाने की कला बखूबी जानते हैं। उनका 'जनसंपर्क' बहुत अच्छा है। कुछ समय पहले अपने राजज्योतिषी के घर उनकी पत्नी के निधन पर वह शोक संवेदना व्यक्त करने गये थे। उस पतली और गंदी गली के लोग बड़े गर्व के साथ उस प्रसंग का स्मरण करते हुए अपने 'महाराजा' की विनम्रता का खुलकर बखान करते हैं।

माधवराव सिंधिया शुरू से ही अपनी छवि के प्रति सचेत रहे हैं। ऐन मारो ने अपनी पुस्तक 'हाईनेस' में लिखा है कि आक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी 'प्ले ब्वाय इमेज' (रसिक मिजाज) की छवि बना ली थी। इस छवि से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में एक अत्यंत साधारण मकान में रहना शुरू कर दिया। उनका कहना था, "भारतीय राजकुमार तो विलासिता के लिए यहां बदनाम हैं, लेकिन मैं यहां कठोर परिश्रम कर रहा हूं और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत हूं।"

'जैसा देश, वैसा वेष' कहावत पर अटूट विश्वास रखनेवाले माधवराव सिंधिया दिल्ली में अपने शाही अतीत का बहुत कम ध्यान रखते हैं। यहां वह एक आधुनिक युवक के रूप में आचरण करते हैं, लेकिन ग्वालियर में वह अपनी सामंती विरासत का भरपूर उपयोग करते हैं। खासकर चुनावों के दौरान तो वह गर्व के साथ अपने राजवंश का उल्लेख करते हैं। यह उनके सामंती संपर्कों का ही कमाल है कि राजमाता के विरोध के बावजूद वह भारी मतों से विजयी होते हैं। इसके बदले में माधवराज सिंधिया ग्वालियर में 'दूरदर्शन प्रसारण केंद्र' लाये, 'ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर तक बढ़वाया और वहां मिराज-२००० लड़ाकू विमान का अड्डा स्थापित करने के लिए भारतीय वायु सेना को राजी किया—ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों से 'वोट' मिलते हैं।

सिंधिया का जन्म राजघराने में हुआ था, वहां की विलासिताभरी जीवन शैली और सौ से अधिक नौकर-चाकर उन्हें शुष्क और विषम भारतीय राजनीति या रेलराज्यमंत्री के दुरूह और अप्रिय कार्यों के योग्य नहीं बना सकते थे। ऐसा लगता है, सिंधिया राजघराने की लोकतांत्रिक व प्रगतिशील परंपराओं ने युवा माधवराव पर अपेक्षित प्रभाव डाला है। इसी रियासत में सबसे पहले स्वायत्त शासन कायम हुआ था और दो सदनोंवाली ग्वालियर नगरपालिका बनी थी, जिसने हाल ही अपनी जन्म शताब्दी मनायी है। ग्वालियर रियासत की इन प्रगतिशील परंपराओं के साथ-साथ इंग्लैंड और भारत के शिक्षा संस्थानों में प्राप्त प्रशिक्षण ने माधवराव का निर्माण किया है और वह अपनी योग्यता को साबित भी कर रहे हैं।

सत्ता में बने रहने की उनकी इच्छा स्पष्ट है, लेकिन उस कांग्रेस में उनके प्रवेश के साथ ही अपनी मां से उनके संबंध टूट गये, जिसने उनकी मां को जेल में डाल दिया था और अपमानित किया था। राजमाता इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकीं कि सत्ता में बने रहने के लिए उनके पुत्र का सत्तारूढ़ पार्टी में बने रहना जरूरी है। धुंआधार मुकदमों ने सिंधियाओं को घर की बातें सार्वजनिक बनाने के लिए मजबूर कर दिया। यही एक ऐसी बात है जो माधवराव के लिए कहीं अधिक कष्टदायी है।

एक समय शिकारी रहे माधवराव सिंधिया आज वन्य जीवों के संरक्षक बन गये हैं। राजकुमार को शाही खेल पोलो भी बेहद पसंद है। उन्हें ब्रिज, तैरने और संगीत का भी शौक है, यद्यपि सिंधियाओं के अस्तबल के घोड़े अभी भी 'घुडदौड़' के मैदान के सरताज हैं।

जब ग्वालियर राज्य का भारतीय गणराज्य में विलय हुआ था, तब माधवराव सिंधिया सिर्फ तीन वर्ष के थे। राजशाही के युग से लोकतंत्र की मुख्यधारा में आने और ग्वालियर के बेताज राजकुमार से दिल्ली में मंत्री बनने तक का फासला उन्होंने जिस सहजता और सूझबूझ से तय किया था, उससे यही लगता है कि नियति ने उन्हें शासक वर्ग में बने रहने का जन्मसिद्ध अधिकार दे रखा है। फिर भी वह अपनी आम आदमी की भूमिका पर इतने मंत्रमुग्ध हैं कि वह ग्वालियर और अपने राजवंश के होने की चर्चा तक पसंद नहीं करते।

■

यादगार : सिंधियाओं के एक पूर्वज के चित्र के सामने राजमाता

को 'उपकृत' नहीं करूंगी। सुख का संबंध दिलोदिमाग से है और मैंने इसे संभाल कर रखा।" शायद आज उन्हें इस बात से बेहद तसल्ली मिल रही है कि उनकी पार्टी भाजपा आज ताकत पकड़ती जा रही है।

पुत्र से विवाद : यद्यपि विजयाराजे सिंधिया राजनीतिक मोर्चे पर काफी कुछ सफल रही हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर वह उतनी भाग्यवान नहीं रहीं। वह पांच बच्चों की मां हैं। वह स्वीकार करती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं। उनकी एक कन्या की बचपन में ही आकस्मिक मृत्यु हो गयी थी और उनकी तीसरी कन्या का विवाह टूट गया। इससे वह अपराध-बोध में भी हैं, क्योंकि वह विवाह उन्हीं ने तय किया था। उनके लिए सर्वाधिक निराशाजनक और परेशानी पैदा करनेवाली बात है, उनके पुत्र का घरेलू और राजनीतिक—दोनों मोर्चों से उनसे अलग हो जाना, जिसकी वजह से मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया है। उनका कहना है, "यह ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी कामना मैं दुश्मनों के लिए भी नहीं कर सकती और जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कितनी सौभाग्यवती हूं, तो मैं अकसर सोचती हूं कि जब मेरा पुत्र ही मेरे साथ नहीं है, तो इन सबका क्या फायदा।"

बहरहाल, इस बात की चर्चाएं हैं कि दोनों के बीच शायद समझौता हो जाये। लेकिन क्या दोनों के बीच पहले जैसा घरेलू संबंध बन सकेगा ? राजमाता का कहना है, "यह संभव है। मुकदमों से कड़ुवाहट बढ़ती है, एक बार इसका सिलसिला बंद हो जाये, तो निजी संबंधों पर इसका असर पड़ेगा।" लेकिन राज-

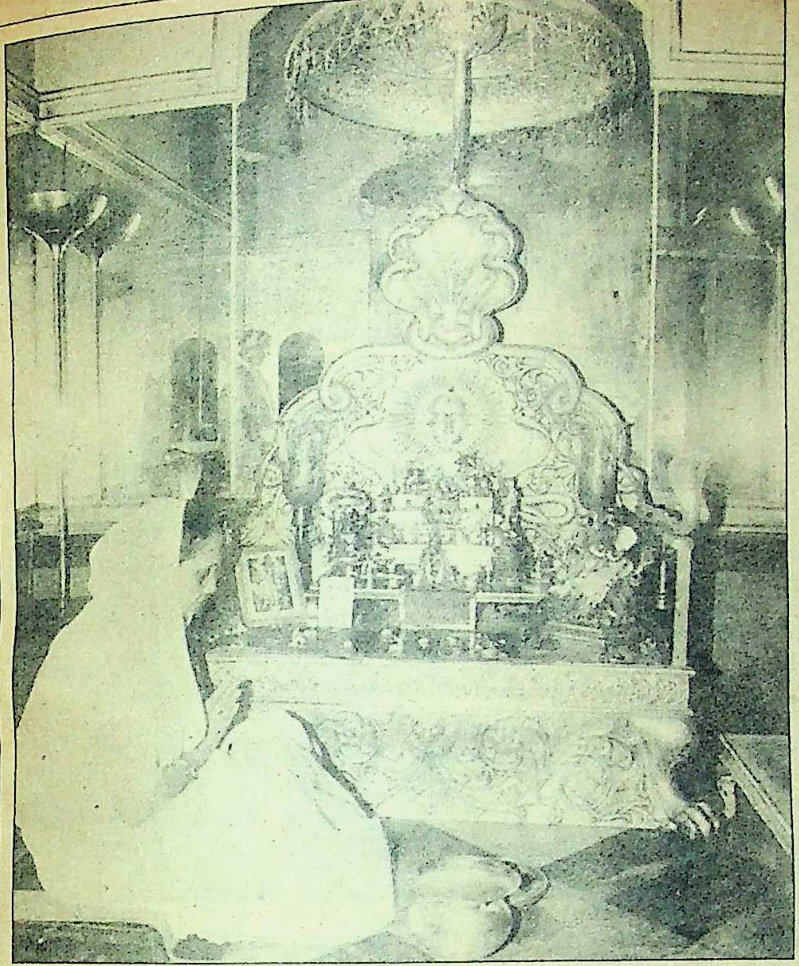

कुलदेवता की आराधना करती महारानी विजयाराजे सिंधिया

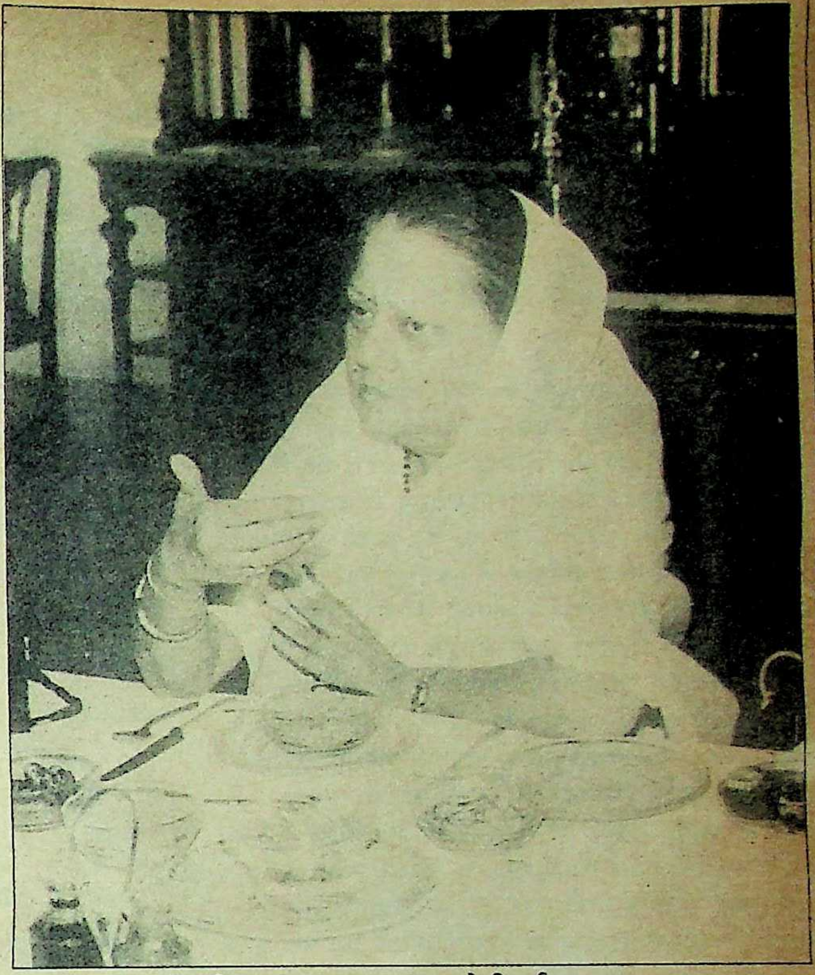

पुरानी शान नहीं रही : राजमाता अल्पाहार लेती हुईं

नीतिक रूप से मां-बेटे को तब तक परस्पर विरोधी रहना है, जब तक कि कांग्रेस-इ का सफाया नहीं हो जाता। राजमाता को इसकी संभावना भी नजर आ रही है।

उतार-चढाव : विजयाराजे सिंधिया के जीवन और जीवन-शैली में बड़े परिवर्तन आये हैं। जिस महान 'जय विलास पैलेस' से वह शासन करती थीं, आज उसमें तीखे पारिवारिक झगड़ों के कारण ताला लगा है। रानी महल में उनकी जीवन-शैली एक महारानी की तरह नहीं, बल्कि एक उच्चवर्गीय आभिजात्य महिला की तरह है, लेकिन 'महल' से उनका लगाव भावनात्मक कारणों से बना हुआ है। वह हिम्मत बांध कर कहती हैं, "देखना है, कब तक यह लगाव बना रहता है।" किसी समय उनके एक इशारे की प्रतीक्षा में सैकड़ों नौकर-चाकर मुस्तैद रहते थे, लेकिन अब ये सब गुजरे जमाने की यादें हैं। आज बिजली की एक कालबेल वहां लगी है, जो घरेलू नौकरों को बुलाने के काम आती है। राजमाता अब अपनी सफेद फियट में चलती हैं और घोड़ों द्वारा खींची जानेवाली बग्घियां उपेक्षित हैं।

ग्वालियर राजघराने के गौरवमय अतीत की याद दिलानेवाली अनेक वस्तुएं वहां देखने को मिल जायेंगी। सिंधियाओं का प्रसिद्ध रजत-सिंहासन अब 'रानी महल' के मंदिर में रखा है, जिस पर कुलदेवता प्रतिष्ठित हैं। सिंधिया के पूर्वज ईरान से एक शानदार बेशकीमती पत्थर का दरवाजा वापस लाये थे। यह दरवाजा अब मंदिर का प्रवेश-द्वार बन गया है। चांदी का वह हौदा जिस पर कभी नवविवाहित विजयाराजे सिंधिया और महाराजा बैठा करते थे, आज वह भूतल के अतिथि कक्ष में रुचिपूर्वक भारतीय शैली में सजाकर रखा गया है। वहां यत्र-तत्र सुशोभित सिंधिया वंश की अनेक पुश्तैनी वस्तुएं, अलंकरण आदि शानोशौकत भरे अतीत के मूक स्मारक हैं।

विजयाराजे सिंधिया ने ब्रिटिश राज के ज्यादा दिन नहीं देखे थे। माधवराज सिंधिया तो तब शिशु थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से परिवार के शेष सदस्यों ने बड़ी खूबसूरती से ब्रिटिश राज को अंगीकार कर लिया था। स्वयं महाराजा को 'सत्ता-हस्तांतरण' गवारा न था। इससे वह कभी समझौता नहीं कर सके—और अचानक उनके लिए सारी दुनिया ही बदल गयी। मधुमेह और आंखों की गिरती रोशनी ने उनको तोड़कर रख दिया। १९६१ में उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय विजयाराजे सिंधिया मात्र ४१ वर्ष की थीं। वैधव्य के साथ-साथ बढ़ते परिवार की परवरिश का दायित्व भी उनके कंधों पर आ गया था।

यादें-ही-यादें : आज तो बस यादें-ही-यादें हैं और यही यादें रियासती जमाने की धरोहर के रूप में उनकी स्मृति में अमिट रूप से अंकित हो गयी हैं। '२१ तोपों की सलामी' वास्तव में गौरवशाली क्षण होते थे। हिंदुस्तान की वह एकमात्र महारानी थीं, जिन्हें यह विशेष गौरव प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने बड़ा सीधा तर्क दिया था। वह महाराजा को यह समझाने में सफल हो गयी थीं कि 'अर्धांगिनी' होने के कारण उन्हें भी इस मामले में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। राजमाता बताती हैं, "इस प्रकार सत्ता हस्तांतरण के पूर्व मुझे अंतिम बार २१ तोपों की सलामी मेरे जन्म दिन पर दी गयी थी और भारी जश्न भी मनाया गया था। एक दरबार भी लगा था, मैं तो चिक के परदे के पीछे बैठी थी। खासियत यह थी कि मैं तो दरबार में सबको देख सकती थी, लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता था।' इस स्थिति का मैंने लाभ उठाया और कुछ देर के लिए वहां से उठ भी गयी थी।" यह संस्मरण सुनाते हुए राजमाता के चेहरे पर उन्मुक्त हंसी फूट पड़ी।

बहरहाल, राजमाता अपने अतीत में नहीं वर्तमान में जीती हैं। उन्हें वर्तमान और भविष्य की कहीं अधिक चिंता है। हरियाणा-चुनावों के परिणामों ने उनके मनोबल को बहुत ऊंचा उठा दिया है। इन चुनावों में राजमाता ने तूफानी चुनाव-प्रचार किया था और हर महत्वपूर्ण चुनाव-सभा में वह शामिल हुई थीं। अब उनकी रफ्तार के धीमा होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं सक्रिय रहकर मरना पसंद करूंगी। काम मुझे तंदुरुस्त रखता है। सक्रियता ही मेरे जीवन का टानिक है, इसके बिना मेरी मौत हो जायेगी।"

घरेलू मोर्चे पर राजमाता सिंधिया की जिम्मेदारियां और बढ़ जायेंगी। वह परदादी बन रही हैं। उनकी स्वर्गीय पुत्री की पुत्री मां बननेवाली हैं। इस प्रकार महारानी से परदादी तथा शानोशौकत और विलासिताभरी शाही जिंदगी से एक जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ता बनना, विजयाराजे सिंधिया के जीवन में आये महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जिनको उन्होंने तेज रफ्तार से चलती अपनी जिंदगी में विशाल हृदयता से बखूबी स्वीकार कर लिया है। —रंजना कक्कड़

नेहरू जन्म शताब्दी समारोह

नेहरू की पुनःखोज

१५ अगस्त से 'पं० नेहरू जन्म शताब्दी समारोहों' के सिलसिले में वर्ष भर चलनेवाले समारोहों का शुभारंभ हो रहा है। इन समारोहों के समापन के ठीक एक वर्ष बाद आम चुनाव आ जायेंगे। क्या क्रांग्रेस-इ सरकार द्वारा पं० नेहरू शताब्दी समारोहों के धन और साधनों का उपयोग कांग्रेस-इ पार्टी के प्रचार में किया जायेगा, जिससे उसकी गिरती साख को बचाया जा सके ? जिन लोगों पर इन समारोहों का दायित्व है, क्या वे पं० नेहरू के बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रति युवकों को आर्कषित करनेवाले कार्यक्रमों का आयोजन करने में सफल हो सकेंगे या ये समारोह भी 'गांधी शताब्दी समारोह' और 'अपना उत्सव' की तरह खर्चीले और आडंबरपूर्ण तमाशा बनकर रह जायेंगे ?

"अपने असीम आकर्षण और विविधता के साथ
भारत मुझे ज्यादा-से-ज्यादा भाता गया है
और जितना अधिक मैंने उसे देखा मुझे लगा कि
यह जिन आदर्शों को संजोये हुए हैं उन्हें समझ
पाना मेरे या किसी और के लिए बेहद
मुश्किल है।"

—पं० जवाहरलाल नेहरू

पं० नेहरू जन्म-शताब्दी समारोह समिति पर जो दायित्व है, वह सहज नहीं है। जिस महापुरुष की स्मृति को साकार करने के लिए उसे वर्षभर कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन करना है वह—पं० जवाहरलाल नेहरू एक महान हस्ती थे। वह साम्राज्यवाद विरोधी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार, सार्वजनिक क्षेत्र के जनक और उदार राष्ट्रवादी थे। वह लोकतंत्र को समर्पित थे। उन्होंने भारत को इस या उस खेमे में जाने से बचाकर रखा। संक्षेप में कहें, तो उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था—उसके लक्षादिक पक्ष थे—जिन्हें किन्हीं ढांचों में ढालकर या सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा साकार कर देना आसान कार्य नहीं है। ऐसी ही समस्या १९६९-७० में महात्मा गांधी के जन्म-शताब्दी समारोहों में भी आयी थी। उस समय सरकारी तंत्र ने सर्वाधिक धन और ऊर्जा आजादी की लड़ाई के इतिहास और प्रमुख नेताओं के योगदान का प्रचार करने में खर्च कर दी थी। लेकिन कितने कठिन संघर्षों और बलिदानों से हमने यह आजादी पायी है—इसका आजादी के बाद की पीढ़ी को अहसास कराने की कोशिशों को आंशिक सफलता ही मिल पायी, क्योंकि ये कोशिशें नवयुवकों को आर्कषित करने में असफल रही थीं।

कठिन चुनौती : 'दांडी मार्च' '१९४२ का भारत छोड़ो आंदोलन' जैसे आजादी की लड़ाई के प्रेरक प्रसंग आज पाठ्य पुस्तकों के महज एक पाठ तक सीमित रह गये हैं, जबकि हर भारतवासी को इन प्रसंगों की जानकारी होनी चाहिए थी। भारत की नयी पीढ़ी को गुलामी का कोई अनुभव नहीं है, उसके लिए तो ब्रिटिश राज इतिहास का एक अध्याय मात्र है। अतः पिछले अनुभवों से सबक लेकर हमें ऐसे प्रेरक प्रसंगों को और अधिक कल्पनाशीलता से प्रस्तुत करना होगा, जिससे वे आजादी की बाद की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। नेहरू शताब्दी समारोहों का सारा दायित्व संसदीय मामलों की राज्यमंत्री शीला दीक्षित और उनकी टीम पर है। क्या वह इस चुनौती का सामना कर सकेंगी ?

काफी वाद-विवाद और अटकलों के बाद तो श्रीमती दीक्षित को शताब्दी समारोहों और आजादी के चालीस सालों की झलक दिखानेवाले कार्यक्रमों की कार्यान्वियन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यह समिति हरकत में आ गयी है, जिससे वह अगस्त के दूसरे सप्ताह अर्थात् ठीक स्वतंत्रता दिवस, १५ अगस्त से ही वर्ष भर चलनेवाले समारोहों का शुभारंभ कर सके। एक मंत्री के अनुसार, "लोगों का इस ओर ध्यान खींचने में हमें एक सप्ताह का समय लगेगा। १५ अगस्त से वास्तविक समारोह शुरू होंगे और तब तक हम अनुकूल वातावरण बनाने में सफल हो जायेंगे।"

समिति में विवाद : वास्तव में इस समिति के अध्यक्ष का यह महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन के लिए सुरक्षित था, लेकिन उनके नाम का वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा ऐसा घोर विरोध हुआ कि अपेक्षाकृत कम विवादास्पद शीला दीक्षित के पक्ष में उनका नाम वापस ले लिया गया। श्रीमती दीक्षित के नेहरू परिवार से अनेक पीढ़ियों के करीबी संबंध हैं। बच्चन के विज्ञापन सलाहकार रोमी चोपड़ा, 'सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स' के चीफ साम पिट्रोडे, भूतपूर्व विदेश सचिव रोमेश भंडारी और जनरल नरेंद्र सिह, श्रीमती दीक्षित के नेतृत्व में गठित कार्यांवयन समिति के सदस्य हैं। लेकिन पिट्रोडे और रोमी चोपड़ा को इस समिति में शामिल करना भी विरोध का मुद्दा बन गया है। विरोधियों का कहना है कि ये लोग अपने-अपने कामों के माहिर हो सकते हैं, लेकिन पंडित नेहरू की स्मृतियों को साकार करने के लिए सिर्फ दूरसंचार या दूरदर्शन प्रसारण में विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं है। जो लोग पं० नेहरू के निकट संपर्क में आये और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से परिचित हैं, उन्हें निचली समिति में रखा जरूर गया है, लेकिन यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि यह समिति सहज 'प्रदर्शन की वस्तु' बनकर रह जायेगी और वास्तविक अधिकार तो 'गांधी के मित्रों' के पास रहेंगे।

बहरहाल, श्रीमती दीक्षित कार्यान्वयन समिति के गठन का बचाव करती हैं। उनका कहना है, "हाईकमान ने ये नाम सुझाये थे। इस समिति का हर सदस्य अनुभवी है और अपना कौशल दिखा चुका है। जनरल नरेंद्र सिंह को एशियन खेलों की व्यवस्था करने का अनुभव है। रोमी चोपड़ा लोकरुचि को अच्छी तरह समझते हैं और युवकों को आर्कषित करने के लिए उनके पास

अनेक योजनाएं हैं। साम पिट्रोडे वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से कार्यों को अंजाम देने की अपनी योग्यता दिखा चुके हैं। रोमेश भण्डारी शताब्दी समारोहों के विदेशों में होनेवाले आयोजनों की व्यवस्था देख रहे हैं।" अमिताभ बच्चन विदेश चले जाने के कारण समिति की नियमित बैठकों में शामिल होने में असमर्थ थे। शीला दीक्षित बताती हैं, "लेकिन आजादी की लड़ाई के दृश्यों की प्रस्तुति के संबंध में उनके पास भी अच्छी कल्पनाएं हैं।"

आर्थिक पक्ष : जहां तक समारोहों के आर्थिक पक्ष का सवाल है, यह समिति किसी वित्तीय उलझन में नहीं पड़ना चाहती। श्रीमती दीक्षित के अनुसार, "अभी तक इन समारोहों के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं है।" उनका कहना है, "इन समारोहों पर कुल कितना खर्च आयेगा—इसका फिलहाल ठीक-ठीक अंदाजा लगा लेना बड़ा मुश्किल काम है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु सरकार इस अवसर पर विशेष आवासों के निर्माण की योजना बना रही है, तो अन्य राज्यों ने भी इन समारोहों के सिलसिले में अलग-अलग कार्यक्रमों की योजना बना रखी है, इसलिए खर्चे के संबंध में बिलकुल सही अंदाज लगाना मुश्किल है।"

इस पांच सदस्यीय समिति के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं ये समारोह बंबई के कांग्रेस शताब्दी समारोहों की तरह सिर्फ कांग्रेस-इ पार्टी का ही मामला बनकर न रह जायें। इन समारोहों के समाप्त होने के ठीक एक साल बाद आम चुनाव होनेवाले हैं। शताब्दी समारोहों की आड़ में कांग्रेस-इ पार्टी का प्रचार किये जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिना कहे यह तो समझा ही जा रहा है कि नेहरू शताब्दी समारोहो के अंतर्गत आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान का व्यापक प्रचार किया जायेगा और इसका लाभ कांग्रेस-इ को ऐसे वक्त मिल सकता है, जबकि उसकी साख गिर रही है।

श्रीमती दीक्षित के अनुसार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ये समारोह कुछ बड़ी हस्तियों तक ही सीमित न रहें। उनका कहना है, "हम इन समारोहों को हर गांव, कस्बे और नगर तक ले जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जन-जागृति कुछ लोगों तक ही सीमित रहे, हम तालुका स्तर तक पहुंचना चाहते हैं।" श्रीमती दीक्षित चाहती हैं कि उन्हें हर गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई प्रतिभाशाली युवक, जिसका वह आजाद भारत की उपलब्धि के तौर पर सम्मान कर सकें। वह बताती हैं, "हम यह भी चाहते हैं कि पी०टी० उषा, मदर टेरेसा, डा० रामन्ना, सुनील गावस्कर और एम०एस० सुब्बालक्ष्मी जैसी विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां इन समारोहों में सक्रिय भाग लें।" इसके साथ-साथ उनकी योजना यह भी है कि आजादी की लड़ाई के दिनों का स्मरण कराने के लिए 'विधानसभाओं' में विशेष सम्मेलन आयोजित किये जायें और एक विशेष सम्मेलन पार्लियामेंट के सेंट्रलहाल में किया जाये, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी निमंत्रित किया जाये। १५ अगस्त को जिस दिन प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर से भाषण देंगे, उस दिन के लिए अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों की रूप रेखा बनायी गयी है।

श्रीमती दीक्षित का कहना है, "हम समारोहों की पवित्र भावनाओं का लोप नहीं होने देंगे, जिससे ये महज तमाशा बनकर न रह जायें।" वह चाहती हैं कि तिरंगा झंडा और लोकप्रिय बने। विभिन्न लय-धुनों पर रिकार्डेड राष्ट्रगान के कैसेट बनाकर वितरित किये जाने की भी योजना है।

विभिन्न कार्यक्रम : आजादी की ४०वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजनाओं के साथ-साथ यह समिति पं० नेहरू को हर्षोल्लास के साथ स्मरण करने के लिए विभिन्न आयोजनों की तैयारी कर रही है। अनेक विचार सामने आये हैं। यह सोचा जा रहा है कि विभिन्न शहरों में जुबीन मेहता के निर्देशन में युवकों के 'आर्केस्ट्रा' कार्यक्रम आयोजित किये जायें और विजय चौक पर खास तौर से तैयार किये गये नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन हो। आजादी की लड़ाई की झलक देनेवाली नृत्य नाटिकाओं, डाक्यूमेंट्री फिल्मों और नेहरूजी और आजादी की लड़ाई के संबंध में आम आदमी के संस्मरणों पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण की भी योजना है। इसके साथ-साथ युवकों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी। यह समिति विभिन्न प्रदेशों में विज्ञान-पुस्तकालयों की स्थापना की योजना भी बना रही है।

'अपना उत्सव' की बदनामी के बाद शताब्दी समारोह समिति इस बात के लिए सतर्क है कि इन समारोहों में आडंबर और फिजूलखर्ची न होने पाये। श्रीमती दीक्षित साफ तौर से इनकार करती हैं कि इन समारोहों में 'अपना उत्सव' की तरह तड़क-भड़क वाले सांस्कृतिक मनोरंजन जैसे कार्यक्रम होंगे। उनका कहना है, "वर्तमान भारत के निर्माताओं का पुण्य स्मरण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और हमारा उद्देश्य जनता में जागृति पैदा करना है, 'पिकनिक' जैसा वातावरण बनाकर उनका महज मनोरंजन करना नहीं।"

विभिन्न राज्यों के समारोहों में लोक कलाकारों के कार्यक्रम ही प्रमुख रूप से संयोजित किये जाते हैं, लेकिन शताब्दी समारोहों के कार्यक्रमों का आयाम काफी विस्तृत होगा। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी द्वारा देशभक्ति संगीत का दो दिवसीय समारोह आयोजित किया जायेगा और नयी दिल्ली में भारत के शहीदों की याद में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जायेगा। नवयुवक आजादी के कर्णधार हैं। प्रधानमंत्री स्वयं आजादी की मशाल नवयुवकों के हाथों में देंगे, जिसे वे अपने-अपने प्रदेशों में ले जायेंगे, जहां प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी या नेहरूजी को करीब से जाननेवाले लोग इस मशाल का स्वागत करेंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन समारोहों में सरकार पंडित नेहरू को इस देश के देदीप्यमान प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस सीमा तक नेहरू के बाद की पीढ़ी को पंडित नेहरू के बहुआयामी वास्तविक स्वरूप से परिचित करा पाती है और किस सीमा तक 'भारत की खोज' करने में उनके लिए मददगार हो सकती है। यह पीढ़ी अब 'निर्णय लेने' की स्थिति में पहुंच रही है। समारोहों के आयोजक पंडित नेहरू के इस कथन को ध्यान में रखेंगे, तो अच्छा काम कर सकेंगे : 'भारतीय होने के नाते मैं स्वयं भी भारत से संबंधित वास्तविकताओं और परिकल्पनाओं से प्रभावित हूं और अनुभव करता हूं कि वह हर बात जिसमें अनवरत सैकड़ों पीढ़ियों को संवारने की ताकत थी और जिसमें समय के अनुसार जीवनचर्या को ढाल लेने की क्षमता है—उसे अपनी शाश्वत विकासोन्मुख जीवन शक्ति, शक्ति के किसी अजस्र स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए।"

—शशि सन्नी

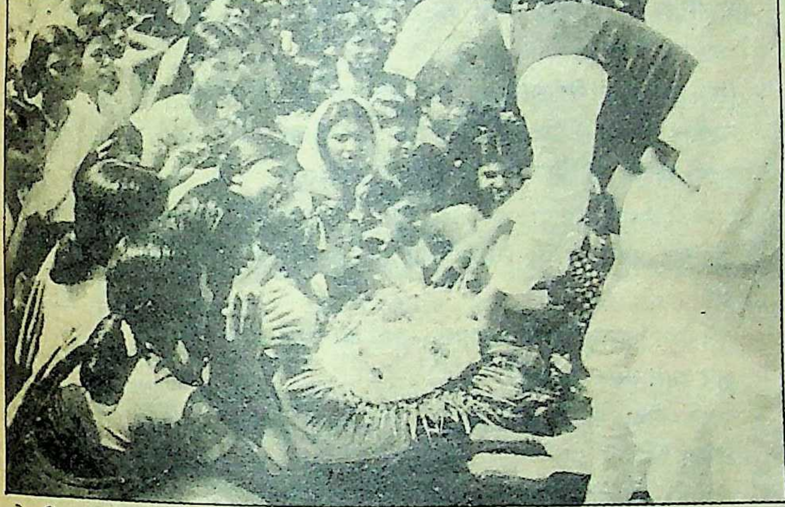
लोकप्रिय नेता : बच्चों और महिलाओं के बीच 'चाचा नेहरू'

आजादी की ओर : नेहरू-जिन्ना, पटेल, कृपलानी और माउंटबेटन

एड्स इससे कैसे बचें

एड्स एक खतरनाक रोग है और यह अभी तक ला-इलाज है। बहुत सी जनता इससे भयभीत है तथा इसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। लेकिन कोई भी स्वयं को इससे बड़ी आसानी से बचा सकता है। इसलिए आइए, हम कुछ आधारभूत बातों पर गौर करें।

एड्स क्या है?

एड्स "एक्वायर्ड ईम्यूनो-डेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम" का संक्षिप्त शब्द है। यह विषाणुओं से होता है जो शरीर की स्वाभाविक सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देते हैं।

यह रोग कैसे फैलता है?

एड्स के विषाणु इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के रक्त या वीर्य के जरिए किसी व्यक्ति के शरीर में पहुच सकते हैं।

अधिकांश मनुष्यों को एड्स के विषाणु इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करने से लग जाते हैं। शेष व्यक्तियों को नशीली दवाओं के सेवन करने वाले व्यक्तियों को लगी सुई से ही प्रायः इंजेक्शन लगवाने के जरिए एड्स रोग लगता है। केवल कुछ थोड़े से ही मामलों में इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के रक्त-आधान (ट्रांसफ्यूजन) के माध्यम से यह रोग फैलता है।

जो व्यक्ति विषाणु ले आते हैं, वास्तव में वे सभी एड्स रोग के शिकार नहीं होते। बल्कि जिस किसी व्यक्ति के विषाणु हैं वह उन्हें दूसरों पर छोड सकता है। फिर भी वे पूर्णतया स्वस्थ अनुभव करते हैं।

इन कामों से आपको एड्स नहीं होता

- सामान्य सम्पर्क जैसे हाथ-मिलाने; छूने और गले मिलने से।
- तरण-तालों में स्नान करने, जल-पान गृहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर खाने-पीने से।
- खासने, छींकने और थूकने से।
- वस्त्र पहनने से।
- संडास पर बैठने, द्वार-दस्ता पकडने, भोजन, गिलासों और प्यालों का प्रयोग करने से।

आप एड्स के शिकार नहीं होते जब आप

- रक्त-दान करते हैं।
- अपने डाक्टर, दंत चिकित्सक या किसी अन्य स्वास्थ्य रक्षक कार्यकर्ता से इंजेक्शन लगवाते हैं या अन्य किसी प्रकार का उपचार कराते हैं।

आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए?

- अजनबी के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित न करें क्योंकि इसमें सदैव जोखिम बना रहता है। आपको मालूम नहीं कि शायद अजनबी इस रोग से पीड़ित हो।
- गुदा मैथुन (अप्राकृतिक यौन-सम्बन्य):-इसमें अत्याधिक जोखिम होता है और इससे बचना चाहिए।
- जितने अधिक लोगों से यौन-सम्बन्ध स्थापित करेंगे, उतना अधिक जोखिम होगा।
- नशाखोरों की इंजेक्शन सुइयों का इस्तेमाल न करें। जो नशाखोर नशीली दवाओं के आदी हो जाते हैं और इसे नहीं त्याग सकते, उन्हें इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लेना चाहिए।

याद रखें

एड्स एक ऐसा रोग है जिसके बारे में जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यह ला-इलाज है। एड्स पर नियंत्रण पाना स्वयं व्यक्ति पर निर्भर करता है।

अधिक जानकारी के लिए

आप सहायक महानिदेशक (एड्स), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110 011 को लिख सकते हैं।

आप एड्स का उपचार नहीं कर सकते।
लेकिन आप इससे निश्चित रूप से बच सकते हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कोटला रोड,
नई दिल्ली- 2 द्वारा जारी

davp 87/91

इलाहाबाद में राजीव की रैली

वीर बहादुर सिंह का नजराना

प्रत्याक्रमण की शुरुआत : नैनी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

छाया : मनमोहन शर्मा

अमिताभ बच्चन के इस्तीफे और वी०पी० सिंह द्वारा खड़े किये गये तूफान के बाद एक अगस्त को राजीव गांधी का पहला इलाहाबाद दौरा था। बहाना था नैनी औद्योगिक क्षेत्र में ५० करोड़ की लागत की हिन्दुस्तान केबल्स लि० की आप्टिकल फाइबर परियोजना और कमला नेहरू की ८८वीं० साल गिरह के अवसर पर ग्रामीण स्वास्थ्य अस्पताल की आधारशिला रखना। उद्देश्य था वी०पी० सिंह के गृहनगर में आ कर अपनी लोकप्रियता का प्रदर्शन करना और उन पर जवाबी हमला करना।

प्रधानमंत्री का यह दौरा मुख्यमंत्री वीर बहादुर के लिए एक प्रकार से अग्निपरीक्षा थी। असंतुष्टों की बगावत पर लगाम लगाने के बाद इस दौरे को सफल बनाने का मतलब था अपने सीने पर एक और तमगा लगाना। बहादुरी का खिताब पाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री की जनसभा में 'विशाल' भीड़ जुटा कर यह दिखाना था कि केवल वही वी०पी० सिंह के सैलाब को उत्तर प्रदेश में रोक सकने की क्षमता रखते हैं। यह काम उन्होंने बखूबी करके दिखा दिया। जाहिर है इस 'सफल' जनसभा के बाद उनकी कुरसी के पाये और जमे हैं।

लेकिन इस तरह की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जो कुछ किया जाता है, वह इस रैली की भीड़ जुटाने के लिए भी हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तो कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरती गयी।

एक अगस्त को इलाहाबाद में एक तरह से उन रास्तों पर अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ था, जिनसे राजीव गांधी को गुजरना था। श्रीलंका कांड से सुरक्षा प्रबन्ध और चौकस किया गया। सुरक्षा कैसे हुई, इसका एक उदाहरण एक पुलिस अधिकारी ने दिया। श्रीलंका कांड के बाद सुरक्षा के महारथियों ने निर्णय लिया कि राजीव गांधी की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों के पास से बंदूकें वापस ले ली जायें और उन्हें रिवाल्वर दिया जाये, ताकि श्रीलंका की तर्ज पर कोई फिर 'बट' न चला दे। पर इतनी जल्दी यह संभव नहीं था, इसलिए सुरक्षाकर्मियों पर निगरानी रखने की हिदायत जारी हुई। यानी निगरानी के ऊपर निगरानी।

एक अगस्त के तीन दिन पहले वीर बहादुर सिंह इलाहाबाद आकर जिला अधिकारी को आदेश दे गये कि लाखों की भीड़ सभास्थल तक पहुंचनी चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी का फरमान स्कूल-कालेजों के प्रधानाचार्यों, लेखपालों, ग्राम प्रधानों तक को जारी हो गया कि भीड़ जुटाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जायें। स्कूलों से बच्चों को ले आने के लिए बसों की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों को लाने के लिए लेखपालों, तहसीलदारों और ग्राम प्रधानों को बसें दी गयीं। एक तरह से भीड़ जुटाने का कोटा तक निर्धारित कर दिया गया था। दरअसल, लगभग सात लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य था वीर बहादुर सिंह का। हालांकि इतनी भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन श्रेय लेने के लिए भीड़ कम नहीं थी। एक वरिष्ठ कांग्रेसी का कहना था कि जितनी भीड़ जुटी थी, राजीव गांधी उससे प्रसन्न थे और अब वीर बहादुर की कुरसी और मजबूत हो गयी है।

अब तक कांग्रेसी रैलियों में इंदिरा गांधी के जमाने से भीड़ जुटाने की जो शैली रही है, वही शैली इधर भी अपनायी गयी। रोडवेज की बसों, प्राइवेट बसों, ट्रकों और पूर्वोत्तर तथा उत्तर रेलवे की ट्रेनें, इलाहाबाद तक आने के लिए मुफ्त में मुहैया करायी गयी थीं।

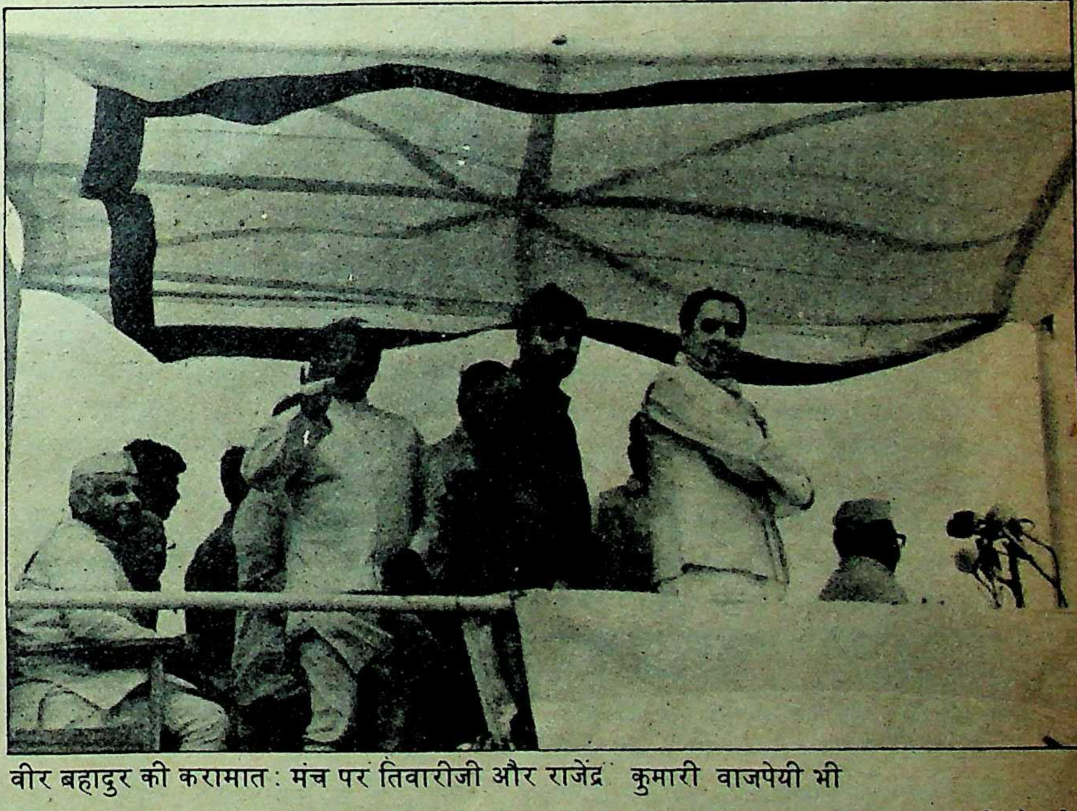

वीर बहादुर की करामात : मंच पर तिवारीजी और राजेंद्र कुमारी वाजपेयी भी

वीर बहादुर सिंह की 'भीड़ जुटाऊ, कुरसी बचाऊ संस्कृति' के यज्ञ में लगभग एक हजार सरकारी और तीन हजार प्राइवेट बसें और ट्रकें इस्तेमाल की गयीं इसे नजरअंदाज करके कि राज्य की यातायात व्यवस्था कितनी ठप हो जायेगी। बसों की कमी का असर पूर्वी

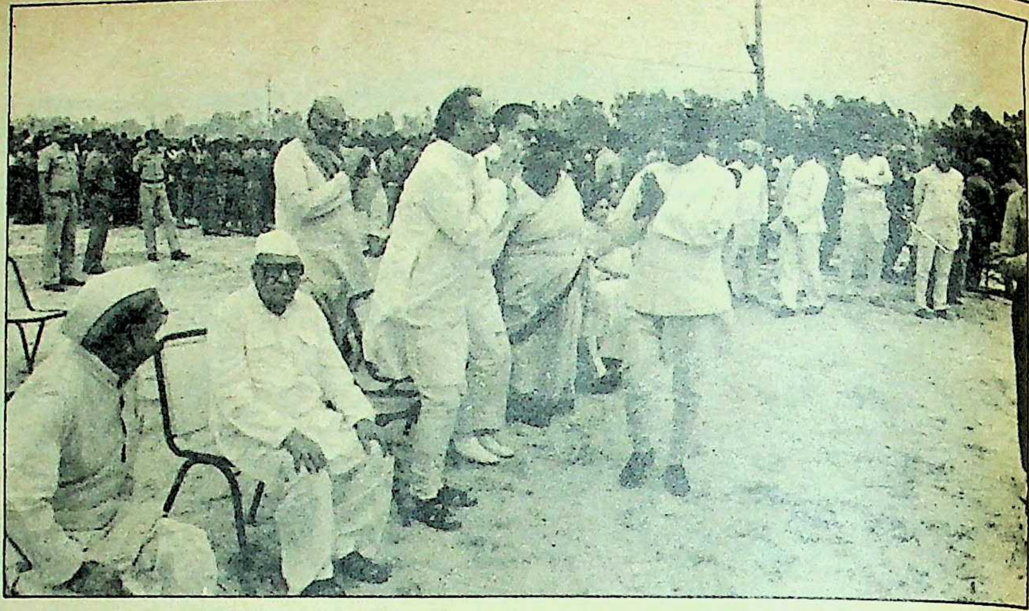

असंतुष्टों को खुश करने में माहिर: वीर बहादुर सिंह रैली में

छाया: मनमोहन शर्मा

प्रायोजित जय-जयकार: प्रधानमंत्री जनता से मिलते हुए

और मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पड़ा।

सभास्थल के पास नैनी से गुजरने वाली गाड़ियों को २६ जुलाई की रात से ही रोक कर उनके ड्राइवरों और क्लीनरों को सभा स्थल पर पहुंचा दिया गया था। नैनी से लेकर गऊघाट तक गाड़ियों की कतारें लग गयीं। राजीव गांधी के इलाहाबाद से विदा होने के बाद ही ये कतारें खतम हुईं।

शायद वीर बहादुर सिंह को अंदेशा था कि इस बार प्रलोभन के नाम पर भी लोग सभास्थल तक न पहुंचे, इसीलिए उन्होंने ४५ हजार सरकारी आदमियों का उपयोग सभा स्थल पर किया। सूत्रों के अनुसार १५ हजार होमगार्ड के जवान (कुछ वर्दी में अधिकांश बिना वर्दी के) ६ हजार गुप्तचर पुलिस और २० हजार के आसपास पुलिस वालों को प्रदेश के हर जिले से बुलाकर यहां तैनात किया गया। इलाहाबाद के प्रत्येक थानों पर एक कांस्टेबिल और ६ होमगार्ड के जवानों को छोड़कर बाकी लोगों को सभास्थल पर लगा दिया गया था।

भीड़ जुटाने में जहां प्रदेश की सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया, वहीं दो दर्जन मंत्रियों की भी मदद ली गयी। कांग्रेस की कोई रैली हो बखेड़ा न खड़ा हो तो शायद कांग्रेस की संस्कृति के खिलाफ होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया आदि शहरों से आने वाली लगभग ५०० बसें नैनी से इसलिए वापस हो गयीं क्योंकि इस पर बैठे कांग्रेसियों और कांग्रेस समर्थकों ने मेजा में पहुंचते ही वी०पी० सिंह-विरोधी नारे लगाये। सूत्रों का कहना है कि मेजा में जैसे ही बसें पहुंचीं 'राजीव गांधी जिंदाबाद', वी०पी० सिंह गद्दार है' के नारे हवा में लहराने लगे। इस का प्रभाव यह हुआ कि इन क्षेत्रों के ग्रामीणों ने 'राजा गद्दार है' पर आपत्ति की। बस इसी के बाद मामला भड़क उठा और प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री संकठा प्रसाद शास्त्री, सांसद श्यामलाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी घायल हो गये। ग्रामीणों के रोष को देखते हुए लोग सभास्थल तक नहीं पहुंच सके। अपने-अपने ठिकानों को किसी तरह लौट पाये। मामला तब ठण्डा हुआ, जब पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठी चला कर ग्रामीणों को खदेड़ा। इस धमाचौकड़ी में ५०-६० बसें क्षतिग्रस्त हुईं। इस प्रकरण पर पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था, इसलिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस के इस व्यवहार के विरोध में मेजा क्षेत्र की दुकानें लगातार दो दिन बंद रहीं।

राजीव गांधी की सभा समाप्त हुई। पर सभास्थल तक लाये गये स्कूली बच्चों की पीड़ा तब शुरू हुई, जब रात दस बजे तक वे अपने घरों तक नहीं पहुंचे। १२ बजे दिन से सभास्थल पर पहुंचे इन बच्चों को पानी तक के लिए तरस जाना पड़ा।

पैंतरे: जहां एक ओर वीर बहादुर सिंह, वी०पी० सिंह के गृहक्षेत्र में अपने आलाकमान की जनसभा को सफल बनाने के लिए जबरदस्त भीड़ जुटाने के लिए प्रयासरत रहे वहीं वी०पी० सिंह समर्थक विधायकों को अपनी ओर मिलाकर राजीवजी के सामने अपने झण्डे के नीचे दर्शाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

नैनी की जनसभा में जब राजीव गांधी बोल रहे थे, तभी वीर बहादुर सिंह मंच से नीचे उतर कर वी०पी० सिंह समर्थक विधायकों के पास तक गये और उनसे बातचीत करके अपने साथ मंच की सीढ़ी तक ले आये, ताकि राजीव गांधी देख सकें कि वीर बहादुर सिंह की पकड़ में वी०पी० सिंह समर्थक भी आ गये हैं। जब राजीव गांधी भाषण करके मंच से उतरे, तो वी०पी० सिंह समर्थक एक विधायक को वीर बहादुर सिंह ने राजीव गांधी से मिलवाया।

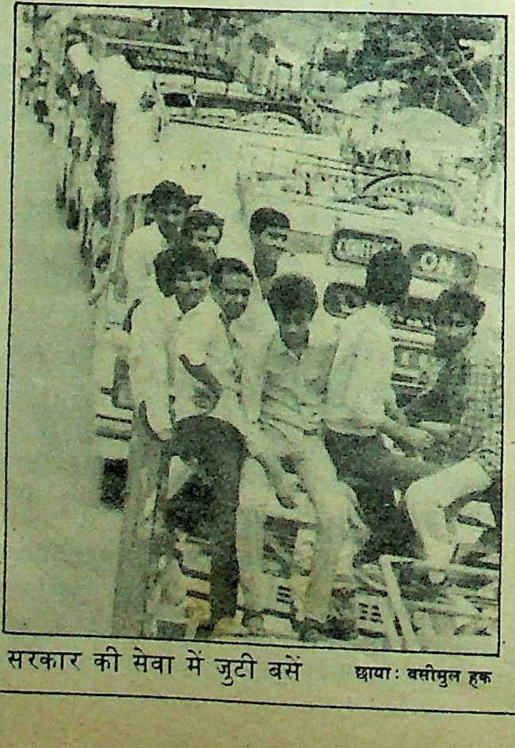

सरकार की सेवा में जुटी बसें

छाया: वसीमुल हक

यह कैसे हो सकता है राजीव गांधी आयें और विपक्ष चुप बैठा हो। तीरंगे झंडे से जहां इलाहाबाद को पाटने की कोशिश थी, वहीं इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में काले झण्डे भी फहराये गये। जबकि इसके लिए प्रशासन की ओर से काफी मुस्तैदी बरती गयी थी कि काले झण्डे इलाहाबाद की सीमा में न दिखायी पड़ें।

विरोधी पक्ष के लोगों ने इलाहाबाद बंद की घोषणा की थी पर इसका असर प्रभावी नहीं रहा। हां, यह जरूर रहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी काले झण्डे फहराते देखे गये।

—दिनेश दीनू

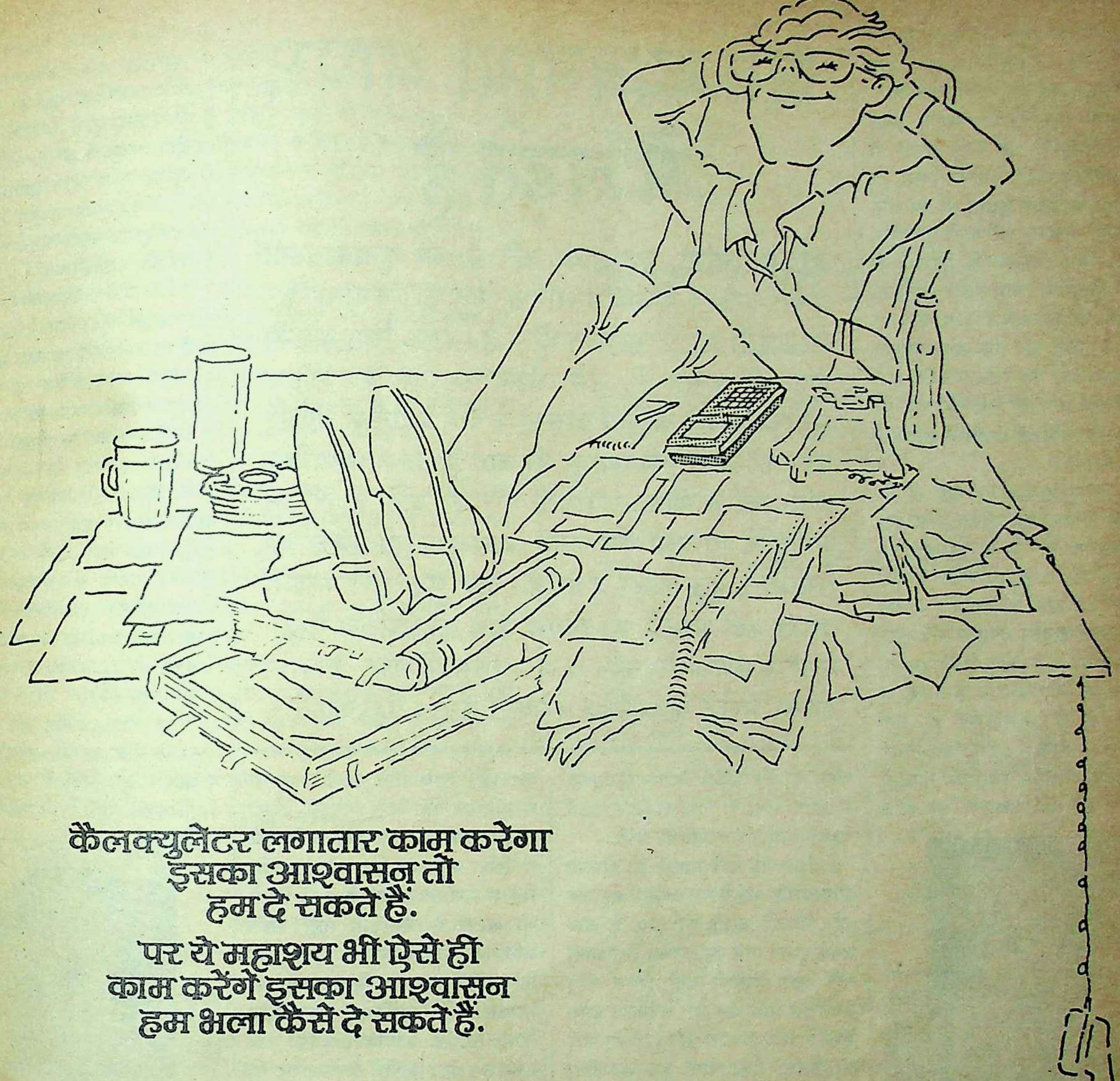

कैलक्युलेटर लगातार काम करेगा
इसका आश्वासन तो
हम दे सकते हैं.

पर ये महाशय भी ऐसे ही
काम करेंगे इसका आश्वासन
हम भला कैसे दे सकते हैं.

हमारी बैटरियों की बनावट पर हम पूरा ध्यान देते हैं
तभी तो नोविनो लगातार बखूबी काम करती हैं.
क्योंकि नोविनो क्वालिटी यानी लंबा सेवाकाल,
ज़्यादा शक्ति, अधिक रिसाव-प्रतिरोधकता जैसे
शब्दों का घिसा-पिटा इस्तेमाल नहीं बल्कि
नोविनो क्वालिटी तो वो है जिसका सुबूत आपको
तब मिले जब आप इसे खुद देखें !

नोविनो.
अगर आपने ये चाहा कि हर चीज़
(और हर व्यक्ति) इस जैसा ही काम करे . . . तो
इसमें भला आपका क्या कसूर ?

NOVINO
HYPER
Leak Proof
National
LAKHANPAL
MADE IN

National **नोविनो**

लखनपाल नेशनल लिमिटेड
बड़ौदा, गुजरात.

नेशनल और पैनासोनिक उत्पादनों के निर्माता
मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जापान
के साथ सयुक्त उपक्रम.

ओह! नोविनो

Sista's-LNL-242/86 HN 8

जब व्यवसायी आपस में लड़ते हैं

वह व्यवसायी, व्यवसायी नहीं है, जो मुनाफा नहीं कमा पाता। अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना हर व्यवसायी का चरम लक्ष्य होता है। इसके लिए वह जो कुछ भी करता है, उसे उचित ठहराता है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं के दाम बढ़ाने के अवसर पर सारे व्यवसायी एकजुट हो जाते हैं, तो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में छोटा व्यवसायी मार खा जाता है, लेकिन भारत के व्यावसायिक जगत में तो दूसरे ही प्रकार का घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। यहां एक बड़ी मछली दूसरी बड़ी मछली को निगल जाने की कोशिश में है। ऐसी कोशिश में कौन-कौन व्यवसायी लगे हैं और इसका भारत के अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

लगभग चार वर्ष पूर्व लंदन में बसे भारतीय व्यवसायी स्वराज पाल ने सहसा जब दो बड़ी कंपनियों-एस्कार्ट्स और दिल्ली क्लाथ मिल (डी०सी०एम०) के बड़ी मात्रा में शेयर खरीदने का जुगाड़ कर लिया, तो जैसे एक जबरदस्त तूफान सा आ गया था। इससे नियंत्रक परिवारों-एस्कार्ट्स के नंदा और डीसीएम के श्रीरामों में दहशत फैल गयी। क्या वह इन प्रख्यात कंपनियों पर नियंत्रण से हाथ धोने जा रहे हैं, जो उन्हें अब तक ऊंचा मुनाफा और ऊंचा दर्जा एक साथ देती रही हैं? यह लगभग निश्चित प्रतीत हो रहा था कि स्वराज पाल इन कंपनियों को फतह करने निकले हैं।

पाल का हमला : यह सही है कि पाल को सरकार का समर्थन प्राप्त था। ऐसी अफवाहें थीं कि वह पूर्ववित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी और पूर्वप्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के लाडले थे। इसलिए उनको अपने जोड़तोड़ और दांवपेंच में अपेक्षाकृत आसानी रही। किंतु उनके दुर्भाग्य से आक्रमण की शिकार कंपनियों ने उन शेयरों के हस्तांतरण को दर्ज (रजिस्टर) करने से इनकार कर दिया, जिसे उनके रजिस्टर्ड स्वामियों ने पहले ही पाल की फर्म 'कपारो ग्रुप आफ लंदन' को बेच दिये थे। मामला अदालत में गया। पाल के विचारानुसार इसमें महज समय की बर्बादी की गयी।

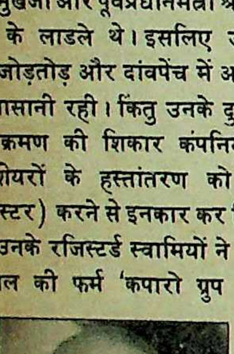

स्वराजपाल

यह सही है कि पाल को सरकार का समर्थन प्राप्त था। ऐसी अफवाहें थीं कि वह पूर्व-वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के लाडले थे।

किंतु यह देरी मामले को श्रीराम और नंदा के पक्ष में तय करने में सहांयक हुई। श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने पाल को समर्थन देना जारी नहीं रखा, जिसकी उन्हें (पाल को) अपने इस आक्रामक खेल में विजय प्राप्त करने के लिए जरूरत थी। इसलिए पाल को अंततः ऐसी शर्तों पर समझौता करना पड़ा, जिससे उन्हें भारी हानि हुई। उनकी लगायी पूंजी को ब्याज तक नहीं मिला, जो किसी बैंक में जमा करने मात्र से मिलता।

'शा वालेस' का मामला : दुबई में बसे मनु छाबड़िया इस आक्रमणकारी दृश्य में ठीक उसी समय प्रकट हुए। पूर्व ब्रिटिश फर्म, कलकत्ता की 'शा वालेस' उनका पहला निशाना थी। उन्होंने भी 'शा वालेस' के नियंत्रक शेयरों को खरीद लिया। पर उन्होंने शेयर दलालों के माध्यम से नहीं खरीदा, जैसाकि स्वराज पाल ने किया था। उन्होंने इंगलैंड में सीधे उन एकमुश्त शेयर होल्डरों से खरीदा जो कंपनी के निदेशक-मंडल में अपने लोगों को नामजद कराते रहते थे।

किंतु कंपनी के प्रबंध निदेशक एस०पी० आचार्य ने इतनी आसानी से हथियार नहीं डाले। उन्होंने पहला सवाल छाबड़िया की हैसियत के बारे में किया और यह रुख अपनाया कि ब्रिटिश नियंत्रक सदस्यों ने अपने शेयरों को असल में बेचा ही नहीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि यदि शेयर बिके भी हैं, तो छाबड़िया उनके नये स्वामी नहीं हैं। उन्होंने ऐसा तर्क इसलिए दिया, क्योंकि छाबड़िया काफी लंबे समय तक परदे के पीछे से काम कर रहे थे। लेकिन अंततः पता चला कि मनु छाबड़िया शा वालेस के बड़ी संख्या में शेयरों के नये मालिक हैं। आचार्य तब पीछे हट गये और इस भीमकाय फर्म का नियंत्रण अन्य हाथों में पहुंच गया है।

कमानी की कहानी : कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (के ई सी) की कहानी भिन्न है, जिस पर कमानी का नियंत्रण था। कमानी एक अच्छी कंपनी के रूप में विख्यात थी, जो बड़ी फैक्ट्रियों के लिए कुछ प्रमुख सामानों का उत्पादन करती थी। नवंबर, १९८३ में कंपनी के निदेशक-मंडल ने कंपनी के उपाध्यक्ष आर०के० हजारी का इस्तीफा मंजूर करने और प्रमुख उद्योगपति राम प्रसाद गोयनका को हजारी के स्थान पर चुनने का फैसला किया। हजारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (आई डी बी आई) के नामजद (नामनी) सदस्य थे। यह एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है जो व्यावसायिक फर्मों को ऋण देता है। अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं, जिन्होंने कंपनियों को ऋण दिये हैं, वे हैं—यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (आई सी आई सी आई)।

जिस मीटिंग में हजारी के स्थान पर गोयनका को चुना गया, उसमें आई सी आई सी आई के नामजद हिंगोरानी (निदेशक मंडल के एक सदस्य) अनुपस्थित थे। और स्वयं आई डी बी आई ने अपने नामजद हजारी को गोयनका के पक्ष में इस्तीफा देने को कहा था। इससे बहुतों को ताज्जुब हुआ था। क्योंकि कंपनी खूब अच्छी तरह चल रही थी और आई डी बी आई को अपने नामजद सदस्य को बदलने का कोई कारण नहीं था। (सामान्यतः ऐसे कदम तभी उठाये जाते हैं, जब कंपनी घाटा दिखाती हो या उसका भविष्य अच्छा न लग रहा हो)।

पर आज तक यह पता नहीं चल पाया कि गोयनका को आई डी बी आई ने आखिर चुना क्यों? यह अवश्य है कि गोयनका पहले से ही निदेशक मंडल

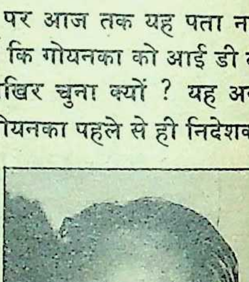

आर०पी० गोयनका

आर०पी० गोयनका कंपनियों पर धावा बोलनेवाले सबसे महत्वपूर्ण और कामयाब व्यक्ति के रूप में उजागर हुए हैं। मनु छाबड़िया लगता है उनका रिकार्ड तोड़ने की कोशिश में हैं।

के सदस्यों में से एक थे। गोयनका द्वारा नियंत्रित तीन कंपनियां—सीट फाइनेन्स कंपनी, सीट इनवेस्टमेंट लि० और सीटीआई इनवेस्टमेंट लि० ने कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के कुल शेयरों का छठा भाग खरीद लिया था। अन्य एक प्रतिशत शेयर गोयनका ने खुले बाजार से सौदे में खरीदे थे।

दूसरे शब्दों में, गोयनका-नियंत्रित कंपनियों ने कमानी शेयरों के छठे भाग से थोड़े अधिक भाग पर चुपके से नियंत्रण कर लिया था और बहुतों को, यहां तक कि कमानी को भी, मौके पर यह ज्ञात नहीं हो सका था कि कमानी के शेयरों को खरीदनेवाली सभी कंपनियां गोयनका की हैं। यह सब बाद में पता चला। यह स्वामित्व पर हल्ला बोलने अथवा किसी कंपनी पर नियंत्रण करने का बेहद आम तरीका है। इसमें गोयनका उस्ताद साबित हुए हैं।

केईसी के मामले में अवश्य गोयनका की कुछ वित्तीय संस्थाओं ने सहायता की थी। किंतु, ऐसा अकसर होता नहीं है। ऐसा संरक्षण किसी महाबली को ही नसीब होता है और उसका वजन आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसकी, देश की राजनीतिक सत्ता की बहुत ऊंची हस्तियों से दोस्ती भी होनी चाहिए। तभी तो ऐसी संस्थाओं पर उसका कारगर असर मुमकिन है।

यदि ऐसा नहीं था, तो सरकार के तीन प्रमुख मंत्रालयों ने कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों की प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? कर्मचारियों की यूनियन ने इस विषय में प्रधानमंत्री और उद्योग, श्रम व वित्त मंत्रियों को तार भेजे थे। उसमें शिकायत की गयी थी कि कुछ वित्तीय संस्थाएं (मसलन आई डी बी आई) अपनी परिसंपत्ति निजी क्षेत्र के बड़े व्यवसायियों को सार्वजनिक कोष की कीमत पर सौंप रही हैं।

मजे की बात तो यह है कि यह भेंट गोयनका को ऐसे समय में की गयी, जबकि कंपनी काफी अच्छी हालत में चल रही थी। इसकी वजह थी कि आर०पी० गोयनका ने प्रति शेयर १०० रुपए की बढ़ी-चढ़ी कीमत अदा की, जबकि एक शेयर का बाजार मूल्य मात्र ५८ रुपए था।

गोयनका की चालें: आर०पी० गोयनका कंपनियों पर धावा बोलनेवाले सबसे महत्वपूर्ण और कामयाब व्यक्ति के रूप में उजागर हुए हैं। मनु छाबड़िया, लगता है, उनका रिकार्ड तोड़ने की कोशिश में हैं। गोयनका ने एक बार प्रख्यात फर्म 'प्रीमियर आटोमोबाइल्स' (फीएट कारों की निर्माता) को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था। वालचंदनगर परिवार प्रीमियर आटो के असली नियंत्रक हैं। जब पता चला कि गोयनका फर्म को लीलने की कोशिश में हैं, तो किन्हीं बिरला ने वालचंदनगर उद्योग समूह की सहायता के लिए हस्तक्षेप किया और इससे गोयनका की कोशिशों में कठिनाई पैदा हुई। खासकर, इस कारण कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह जता दिया था कि वह गोयनका के इस अभियान के विरुद्ध हैं।

अंततः बजाज आटो के राहुल बजाज मध्यस्थ बने और समझौते की शर्तें तय हुई। इस प्रक्रिया में गोयनका को अपनी परिसंपत्ति (होल्डिंग्स) की अच्छी कीमत मिली और उन्होंने अच्छी-खासी कमायी की। बहरहाल, उन्हें कार निर्माता कंपनी को हथियाने की अपनी कोशिश छोड़नी पड़ी थी। गोयनका का मुनाफा कमानेवाली बड़ी फर्म क्लोराइड इंडिया के हस्तांतरण की चर्चा भी जोरों पर है। मनु छाबड़िया उसकी संरक्षक फर्म 'क्लोराइड (यू०के०) फर्म' के शेयरों को एकमुश्त खरीदने के इच्छुक थे। इसमें दिलचस्पी रखनेवाली पार्टियां हैं, सिंघानिया और गोयनका। एक ताजा मामला बड़ी फर्म 'जेनेलेक' का है। ऊंचे दर्जे की बहु-राष्ट्रीय कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन (जीईसी) के पास जेनेलेक के एक तिहाई शेयर हैं। मोदी रबर के मोदियों के बारे में खबर है कि उन्होंने एक समझौता किया था, जिसके तहत जीईसी जेनेलेक के अपने शेयरों को मोदी को बेच देगा। पर जब यह खबर लीक हुई, तो कलकत्ता के शेयर होल्डरों ने अनेक कानूनी आपत्तियां उठायीं। कानून कहता है कि जो ग्रुप शेयरों को खरीदता है उसे कुछ नये शेयर उन शेयर होल्डरों को बेचने पड़ेंगे, जिन्हें 'अल्पसंख्यक शेयर होल्डर' कहा जाता है। पर ऐसा नहीं किया गया। क्योंकि ऐसा होता तो मोदी को कुल एक तिहाई शेयर उपलब्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में यह निश्चित नहीं कि क्या कभी उनकी (मोदी की) इन शेयरों को खरीदने लायक हैसियत हो पायेगी। इस सौदे का अंतिम चरण पूरा होना अभी बाकी है, किंतु व्यावसायिक अखबारों में इस संबंध में अनेक कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं।

—अर्थ विज्ञानी

नेफेड

समृद्धि का प्रतीक

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) भारत में २६ राज्य संघों और ३५०० से अधिक विपणन समितियों का राष्ट्रीय निकाय है।

नेफेड उत्पादक और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए अंत:राज्य, अन्तर्राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सभी प्राथमिक और संसाधित कृषि पण्यों का विपणन करता है।

यह खाद्यान्न, दालें, तेल और तिलहन, कपास, जूट, वनोत्पाद, कुक्कुट, कृषि यंत्र, ताजे, सूखे, संसाधित फलों और सब्जियों जैसी कृषि पण्यों का व्यापार करता है।

कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयोजन से बाजार में प्रवेश करता है।

भारत सरकार ने तिलहन इत्यादि किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने तथा प्याज, रामतिल, तिल, हाथ से चुनी मूंगफली इत्यादि के निर्यात और जावित्री, जायफल और ताजे फलों के आयात के लिए नेफेड को सरणीबद्ध एजेन्सी नियुक्त किया है।

नेफेड के देश में शीत भंडार, गोदाम, दाल मिल के अतिरिक्त दिल्ली और वेल्लूर (तमिलनाडु) में फलों और सब्जियों के संसाधन के कारखाने हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी
विपणन संघ मर्यादित

NAFED

नेफेड

५४, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली—११००६५
टेलीफोन: ६४३२४०१–४ (४ लाइनें)
तार: नेफेड, नई दिल्ली
टेलेक्स: ३१–३२५४–एनएफडी–इन
३१–६१०६५– ,, ,,

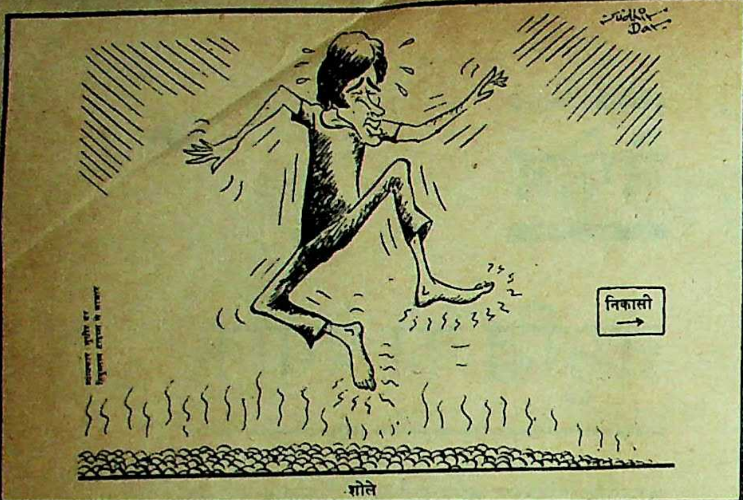
Sudhir Dar
निकासी →
व्यंग्यकार सुधीर दर
हिन्दुस्तान टाइम्स से साभार

शोले

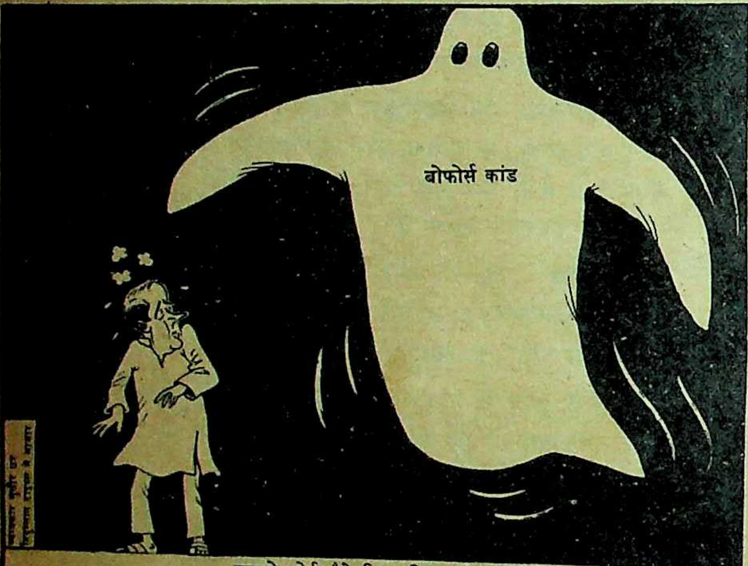
बोफोर्स कांड
व्यंग्यकार सुधीर दर
हिन्दुस्तान टाइम्स से साभार

इसको कोई कैसे निष्कासित करे?

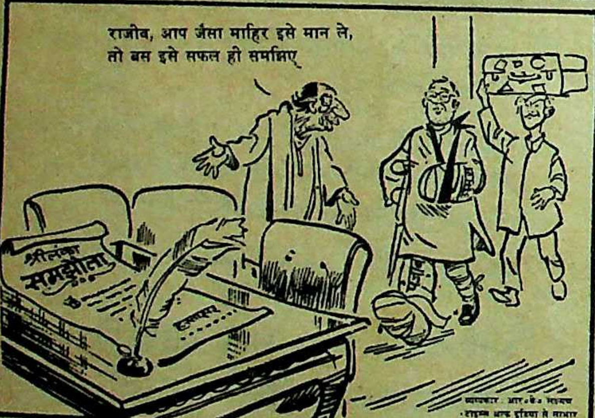
राजीव, आप जैसा माहिर इसे मान ले,
तो बस इसे सफल ही समझिए
श्रीलंका समझौता
व्यंग्यकार : आर० के० लक्ष्मण
टाइम्स आफ इंडिया से साभार

सुपर कंप्यूटर

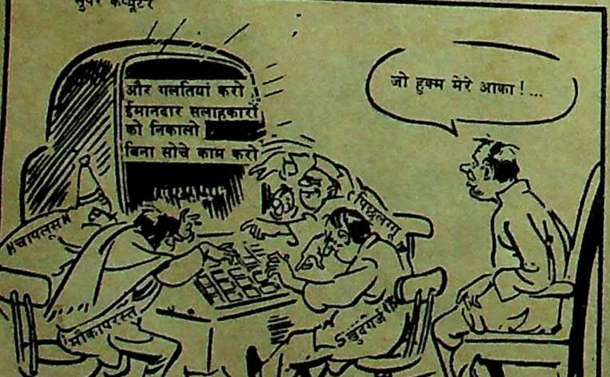
और गलतियां करो
ईमानदार सलाहकारों
को निकालो
बिना सोचे काम करो
जो हुक्म मेरे आका ! ...
चापलूस
मौकापरस्त
पिछलग्गू
खुदगर्ज

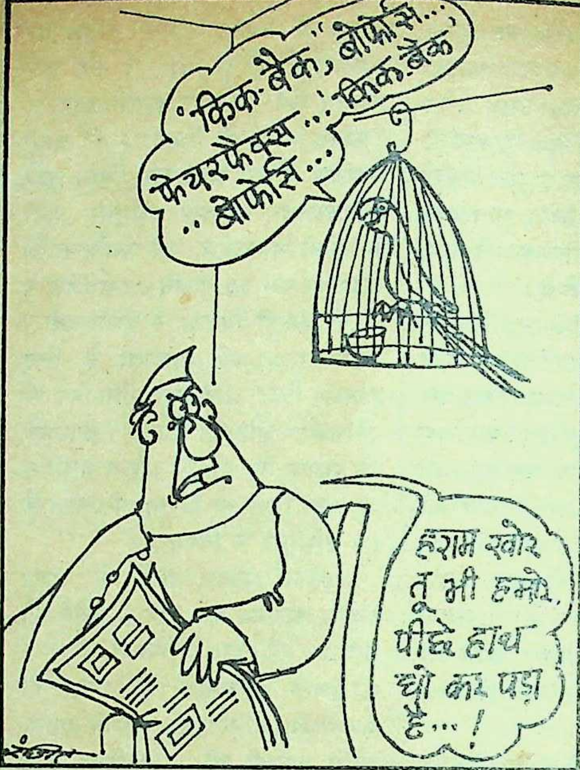
'किक-बैक', बोफोर्स... फेयरफेक्स ... 'किक-बैक' ... बोफोर्स ...
हराम खोर तू भी हमारे पीछे हाथ धो कर पड़ा है... !

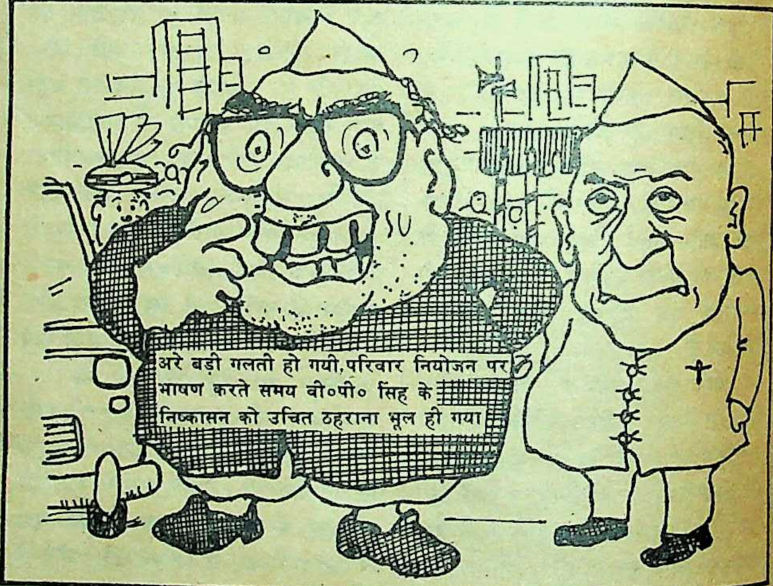
अरे बड़ी गलती हो गयी, परिवार नियोजन पर भाषण करते समय वी०पी० सिंह के निष्कासन को उचित ठहराना भूल ही गया

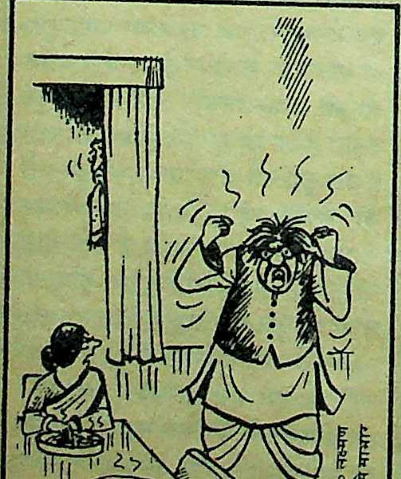
व्यंग्यकार : आर० के० लक्ष्मण
टाइम्स आफ इंडिया से साभार

चिल्लाओ मत,
यह कोई संसद नहीं है।

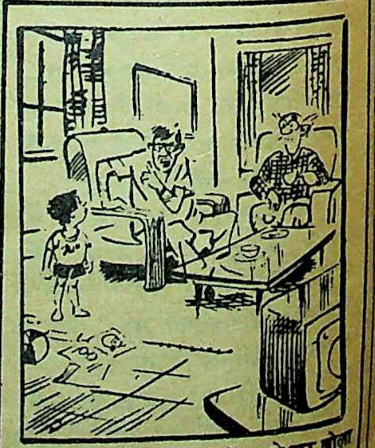

बहस मत करो ! भले ही रेगन ने झूठ बोला हो, राजीव ने झूठ बोला हो, ओलिवर नार्थ या बच्चन-भाइयों ने झूठ बोला हो, लेकिन तुम्हारी उम्र के बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए ! समझे !

मनोरमा

१५ सितम्बर' ८७

नववधु विशेषांक

नववधु-सा सुंदर-सजीला और अछूते विषयों को संजोये हुए हर नववधु के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भरी रचनाएं

प्रमुख आकर्षण

- अपने पति की प्रेमिका बनी रहिए
- पहला साल — नाजुक हाल
- चुम्बन : पहली रसभीनी पहचान
- कैसे होंगे आपके वो (राशि के अनुसार)
- सेक्स : कुछ घबराहट भरे प्रश्न
- नवदम्पतियों के लिए बेहतर परिवार-नियोजन
- पंच सितारा शादियां
- दुल्हन के जोड़े
- जेवर खरीदिए मगर सोच-समझ कर
- नयी-नयी गृहस्थन के लिए व्यंजन
- समाज के बदलते माहौल में अपनी बेटी को क्या सीख देना चाहेंगी आप ?
- दुल्हन या चांद का टुकड़ा : रूप सज्जा दुल्हन की

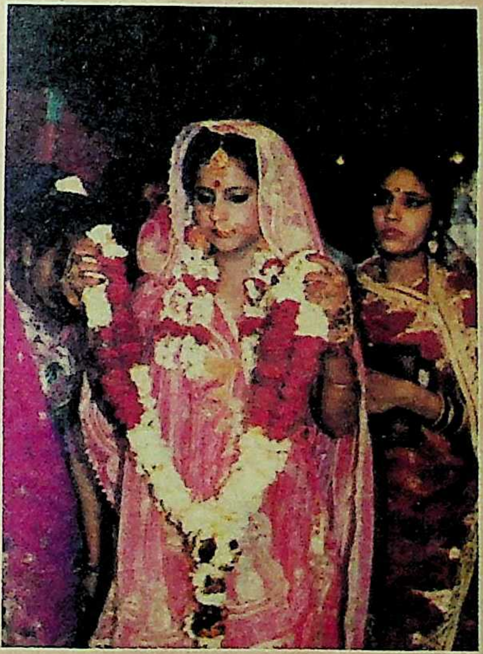

आवरण कथा

कैसा होता है प्यार-सात फेरों के बाद ?

विवाह, केवल एक नये जीवन की शुरुआत, नयें-नये कपड़े, जेवर और पति के साथ शरीर का मिलन, रुमानी प्रेमाभिव्यक्ति ही नहीं है, एक परिपक्व व प्रगाढ़ लगाव की शुरूआत है, जो केवल गीत-संगीत की बुनियाद पर नहीं, वरन् रोज की जिंदगी जीने पर निर्भर करता है।

अन्य आकर्षण

- तलाश है एक कमाऊ पत्नी की
- जीवन साथी के लिए विज्ञापन देने का साहस कर सकेंगी ?
- झूठ की बुनियाद पर सपने नहीं बनते
- क्या लड़के ही नहीं लड़कियां भी चाहती हैं दहेज ?
- लड़का अच्छा है तो परिवार से क्या लेना-देना ?
- संगीता गुप्ता की कहानी : एक चिट्ठी तुम्हारे नाम
- नरेन्द्र कोहली की पौराणिक कहानी : एषणा
- मुजफ्फर बुखारी का हास्य-व्यंग : नोक-झोंक

मूल्य-६.००

नयी सौतन

रेखा को अपनी 'मुलकवाली गॉड सिस्टर' कहने वाली श्रीदेवी ने जब से, 'नगीना', 'मि० इंडिया' की अप्रतिम सफलता के बाद, रेखा के प्रति तिरस्कार-पूर्ण रवैया अपनाया है, तब से रेखा भी कमर कस कर सामने आ खड़ी हुई है। सावन कुमार टाक ने 'सौतन की बेटी' से टीना मुनीम को राजेश खन्ना का साथ छोड़ देने के बाद, निकालकर टीना की जगह श्रीदेवी को लेने की बात चलायी, तो रेखा ने काका (राजेश खन्ना) को पटा कर वह भूमिका हथिया ली। बेटे सन्नी देवल के साथ मुहब्बतवाली भूमिकाएं निभाते-निभाते श्रीदेवी ने जब डैडी धर्मेंद्र के साथ भी रोमांटिक भूमिकाएं करनी शुरू की, तो रेखा ने धर्मेंद्र के साथ तोड़े रिश्ते को पुनः सुधार लिया और एक-के-बाद-एक छह फिल्में साइन कर लीं। अपने से छोटी उम्र के उन नायकों के साथ, जिनके संग श्रीदेवी हीरोइन की भूमिकाएं कर रही है, रोमांटिक भूमिकाएं करने के लिए रेखा ने पुनः ऐरोबिक योगा शुरू कर दिया है। हां, होटल सी-रॉक जाने के बजाय उसने अपने बैंड स्टैंड स्थित बंगले 'सी-बर्ड' में ही बाकायदे हेल्थ सूट खोल लिया है, ताकि वह १६ वर्ष की किशोरी लग सके और जरूरत पड़ने पर 'आंटी' कहनेवाले चंकी पाण्डे की भी हीरोइन बन सके। और-तो-और मिथुन चक्रवर्ती की अमिताभ से तुलना करते हुए फिल्म निर्माताओं के सामने एक और खिड़की खोल दी कि अगर कोई उसके साथ मिथुन को साइन करे, तो वह पूरा कोआपरेट करेगी। देखें, अब श्रीदेवी इसका काट क्या करती है?

धर्मेंद्र और रेखा

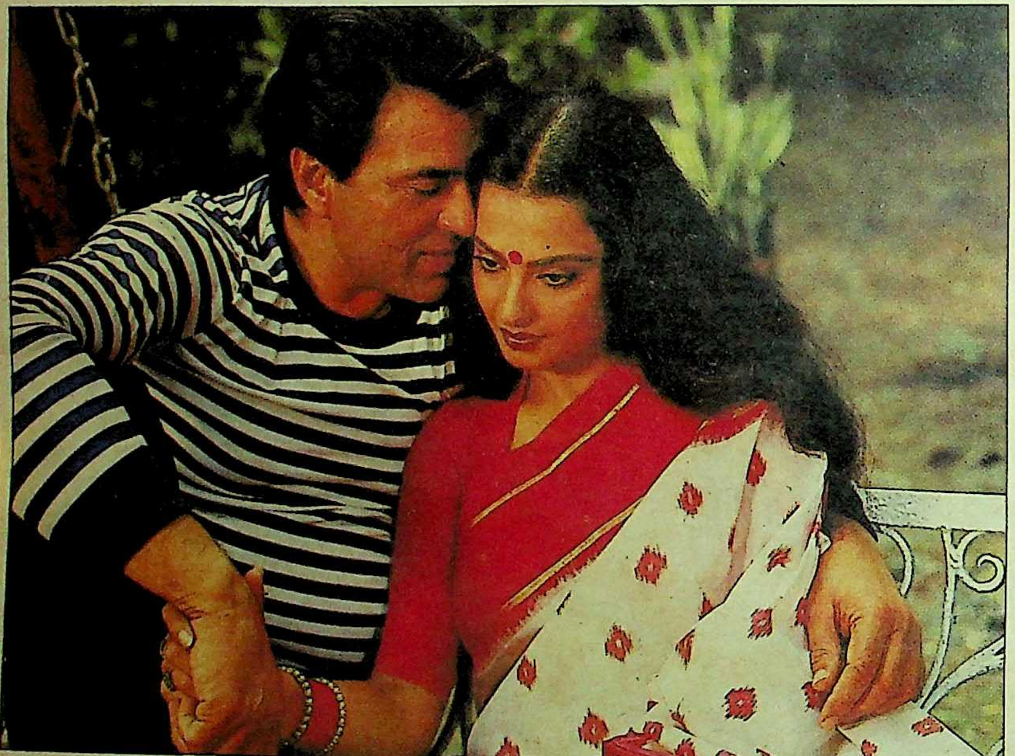

छाया : बालकृष्ण

गोविंदा का आतंक !

एक वर्ष पहले का भोला-बेचारा, मासूम गोविंदा अब फिल्म इंडस्ट्री का 'ही-मैन' धर्मेंद्र बन गया हैं। गोविंदा को गोविंदा बनानेवाले निर्देशक शशिलाल नायर तक के दिमाग को दुरुस्त कर देने-वाले गोविंदा ने उन लोगों को भी ठीक करने का बीड़ा उठा लिया है जो उसके बजाय अब धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, सुमीत सहगल तथा चंकी पाण्डे का 'चक्कर' लगाने लगे हैं। उसने अनिल कपूर (मि० इंडिया) की तरह खुद की फिल्म 'हत्या' शुरू कर उन फिल्म निर्माताओं की प्लानिंग की हत्या कर दी, जिन्होंने उसे लेकर शूटिंग शिड्यूल की प्लानिंग कर ली थी। निर्माता देवी दत्त (आक्रोश) अपनी नयी फिल्म 'अंदाज प्यार का' का सेट लगा कर बैठे रहे, शशिलाल नायर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन गोविंदा 'गोविंदा नाइट' के आयोजन में लगा रहा, क्योंकि उसे कुछ 'अपनों' की और कुछ 'अपनी' (पब्लिसिटी) परवाह ज्यादा थी। उसकी लापरवाही का सबक सिखाने के लिए उसके निर्माताओं ने जब उसकी जगह चंकी पाण्डे या सुमीत को लेकर फिल्म पूरी कराने की धमकी दी, तो गोविंदा के 'अपने' आगे आ गये और उसकी बलिष्ठ मांसपेशियों वाले कसरती बदन की तस्वीर सामने रख दी। दारासिंह से भी खौफ न खाने वाले निर्माता गोविंदा से खौफ खा गये। मिथुन बाबा को गोविंदा से सबक लेना चाहिए।

रीना राय

छाया : बालकृष्ण

और अब मोहसिन भी

स्ट्रोक लगाने में माहिर पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहसिन खान इस बार बीवी रीना राय के दोहरे स्ट्रोक के सामने चित्त पड़ गये। पिछले महीने मां बन कर रीना ने असली जिंदगी में जो स्ट्रोक लगाया तो, उसके ससुराल वाले दंग हो गये, क्योंकि जब बंबइया और पाकिस्तानी अभिनेत्रियां प्रसव के लिए पश्चिमी देशों को भागती हैं, तो रीना ने तो मायका (बंबई) चुना ! अब उसका दूसरा स्ट्रोक और भी जबर्दस्त रहा, अपने से छोटे उम्रवाले खूबसूरत पति मोहसिन खान को दौड़-धूप कर हीरो बनाने में अंततः वह सफल हो गयी। इसके लिए उसने कई बड़े निर्माता-निर्देशकों से बात की, लेकिन निर्माता डर रहे थे कि कहीं मोहसिन फिल्म बीच में छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाये। फिर, अभी तक क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर जिस किसी ने भी फिल्में बनायीं, उन बेचारों की लुटिया तक डूब गयी, इसलिए कोई भी यह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहां तक कि रीना की बहन (बरखा) और भाई (राजा) भी पीछे हट गये। मायूस रीना ने जब यह बात निर्माता सलीम को बतलायी, तो वह यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गये और मोहसिन खान को अपनी नयी फिल्म 'बंटवारा' में धर्मेंद्र व विनोद खन्ना के साथ साइन कर लिया। दीदी रीना की हमेशा खबरदारी रखनेवाली साली बरखा की, जीजा मोहसिन खान पर नजर रखने की, जिम्मेदारी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गयी है। उसे डर 'बंटवारा' की तीनों हीरोइनों से है। रविशास्त्री से अमृता सिंह तथा राजेश खन्ना से डिंपल के अलग हो जाने के बाद उनके दिलों की 'खोली' (कमरा) तो खाली है ही, पूनम ढिल्लों भी मोहसिन की जबर्दस्त दीवानी हैं। लेकिन दर्शकों को, निर्देशक जे०पी० दत्ता के निर्देश पर मूंछें बढ़ा लेने वाले मोहसिन खान कैसे लगेंगे भला !

राखी

छाया : दुर्गाप्रसाद

राखी का इंतकाम

जिस 'जॉनी' (राजकुमार) के विरुद्ध बोलने की जहमत धर्मेंद्र, फीरोज खान, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा भी उठाने में हिचकते हैं उसके विरुद्ध मासूम चेहरेवाली राखी ने जैसे मुहिम-सी छेड़ दी है। "अपने को यह तीसमार खां (गंजू) समझता क्या है—न सूरत न सीरत, सिर्फ आवाज और वह भी शराब के कारण खोखली। पता नहीं दर्शक और निर्माता 'इसे' टॉलरेट कैसे करते हैं," कहनेवाली राखी दो दशक पहले के अपने उस अपमान को आज भी भूल नहीं पायी है, जब महबूब स्टूडियो में फिल्म 'लाल पत्थर' के सेट पर निर्माता ने राजकुमार का परिचय करवाया तो राजकुमाराना अंदाज में जॉनी ने अपना बढ़ा हुआ हाथ पीठ पीछे करते हुए कहा—"राखी! भई, हम तो तुम्हें हाथ में नहीं बंधवायेंगे, चाहो तो गले से आकर लग जाओ।" जॉनी के इस थर्डक्लास डायलाग से अपमानित राखी की आंखों में आंसू भर आये, लेकिन जॉनी बोलते रहे—"पता नहीं किसने इस खूबसूरत लड़की का नाम राखी रख दिया, राखी तो हाथ में बंधने के लिए होती है...।" उस घटना को भूल चुकी राखी का पारा उस समय सातवें आसमान पर जा पहुंचा, जब फिल्म 'मुकद्दर का फैसला' की शूटिंग के समय कैमरे के सामने संवाद बोलते-बोलते अचानक जॉनी ने राखी का जोरदार चुंबन ले लिया। कैमरा आन था, फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा थे। राखी को पुनः अपने पैर फिल्म जगत में जमाने थे, इसलिए वह उस समय खून का घूंट पीकर रह गयी, लेकिन बाद के शॉट्स में जॉनी को फिर 'लिबर्टी' नहीं लेने दी। प्रकाश मेहरा ने जब शूटिंग के बाद जॉनी को समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो जॉनी भड़के—"अरे यह बुढ़िया समझती क्या है अपने को। लंबू (अमिताभ, फिल्म : 'कभी-कभी') और पतलू (शशि कपूर, फिल्म : 'शर्मीली') को क्या चुंबन-दृश्य नहीं दिये थे।"

अब बूढ़े हो चले जॉनी को कोई उसकी बढ़ती उम्र और घटते मार्केट वैल्यू के बारे में क्या समझाये! नहीं तो 'जंजीर' में अमिताभवाली भूमिका लेकर यही प्रकाश मेहरा जब इसी जॉनी के पास पहुंचे थे, तो कहानी सुनकर जॉनी ने फिकरा कसा था, "जॉनी, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम सिर में जो सरसों का तेल लगाकर आये हो न, उसकी दुर्गंध ने मेरा मूड खराब कर दिया।"

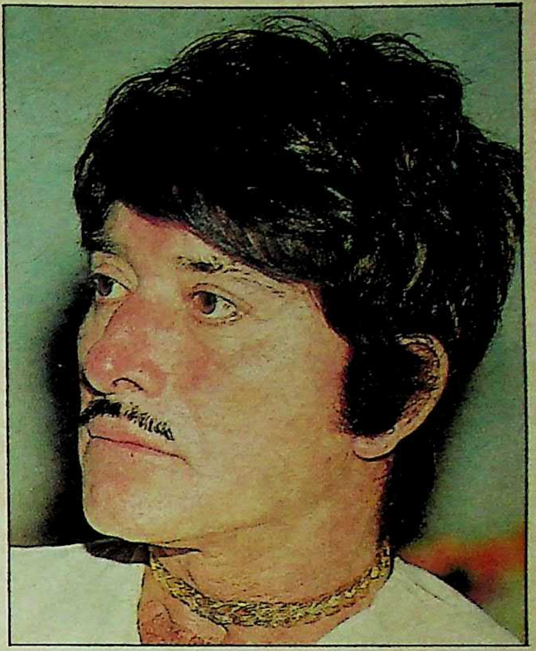

राजकुमार

छाया : दुर्गाप्रसाद

त्रिया हठ!

'रुखसत' में अनुराधा पटेल

सिम्मी की तरह खुद को 'अनकिस्ड गर्ल' का फतवा देनेवाली दादा मुनि यानी अशोक कुमार की पौत्री, अनुराधा पटेल को फिल्म 'रुखसत' में मिथुन चक्रवर्ती के साथ चुंबन-दृश्य देने के लिए राजी करने में 'किस्ड गर्ल' सिमी गरेवाल को दो वर्ष लग गये। 'रुखसत' की निर्मात्री-अभिनेत्री सिमी ने जिस तरह का 'हॉट किस सीन' शशि कपूर के साथ फिल्म 'सिद्धार्थ' में दिया था, वैसा ही दृश्य वह अनुराधा एवं मिथुन चक्रवर्ती पर भी फिल्माना चाहती थी, लेकिन उत्सव' में जब गिरीश कर्नाड एवं शशि कपूर चुंबन दृश्य के लिए अनुराधा को राजी नहीं कर सके तो भला सिमी की क्या बिसात! लेकिन सिमी भी अपने त्रिया-हठ पर अड़ गयी कि भले ही कितना समय लग जाये, वह अनुराधा से चुंबन दृश्य जरूर करवा कर रहेंगी। अंततः एक त्रिया-हठ को दूसरा त्रिया-हठ ही तोड़ सका, लेकिन एक त्रिया ने दूसरी त्रिया के सामने शर्त रख दी—बेडरूम में मद्धिम रोशनी होनी चाहिए। कट-लाइट से चुंबन का आभास दिया जाना चाहिए और इस दृश्य का कोई भी चित्र प्रचार के लिए नहीं दिया जायेगा। सिमी ने अनुराधा की बात मान ली, लेकिन शॉट-टेकिंग के समय जब अनुराधा मिथुन के साथ प्रगाढ़ चुंबन में व्यस्त थी, सिमी के इशारे पर कुछ क्षण के लिए सेट की रोशनियां जलीं और बुझ गयीं। अनुराधा को पता ही नहीं चला कि एक अनुभवी त्रिया दूसरी नयी त्रिया से, उसकी बात रखते हुए भी, बाजी मार ले गयी।

अब अनुराधा 'बुनियाद' के प्रिंस से पूछती फिर रही है—"मैंने कुछ गलत तो नहीं किया?"

क्या करे टीना?

काका (राजेश खन्ना) से अपने दस वर्षों के अंतरंग रिश्ते को पल भर में तोड़कर अनिल अंबानी से नाता जोड़ लेनेवाली टीना मुनीम आजकल है कहां? न तो वह अनिल के साथ बंबई के पंच-सितारा होटलों में 'डिनर' लेती दिखायी पड़ती हैं न ही अपने घर पर। अनिल-टीना-अफेयर से अंबानी खानदान की होनेवाली बदनामियों के कारण जब से रिलायंस-अंपायर के धीरूभाई ने सख्ती अख्तियार की है तब से टीना के सामने मुसीबतें खड़ी हो गयी हैं कि वह या तो अमिल से विवाह करने के लिए धीरूभाइ की मंजूरी की प्रतीक्षा करे या फिर फिल्मों में पांव जमाने की पुनः कोशिश करे। पहले कदम में 'रिस्क' है, अगर शादी की मंजूरी नहीं मिली, तो वह कहीं की भी नहीं रहेगी, इसलिए उसने भूतपूर्व गाडफादर देवआनंद, जो उसे फिल्मों में ले आये और सावन कुमार टाक (सौतन) तथा कुछ और निर्माता-निर्देशकों से गुप्त रूप से मिली, लेकिन सबने उसे नये-नये नेता बने काका से ही मिलने की सलाह दे दी। अब टीना क्या करे?

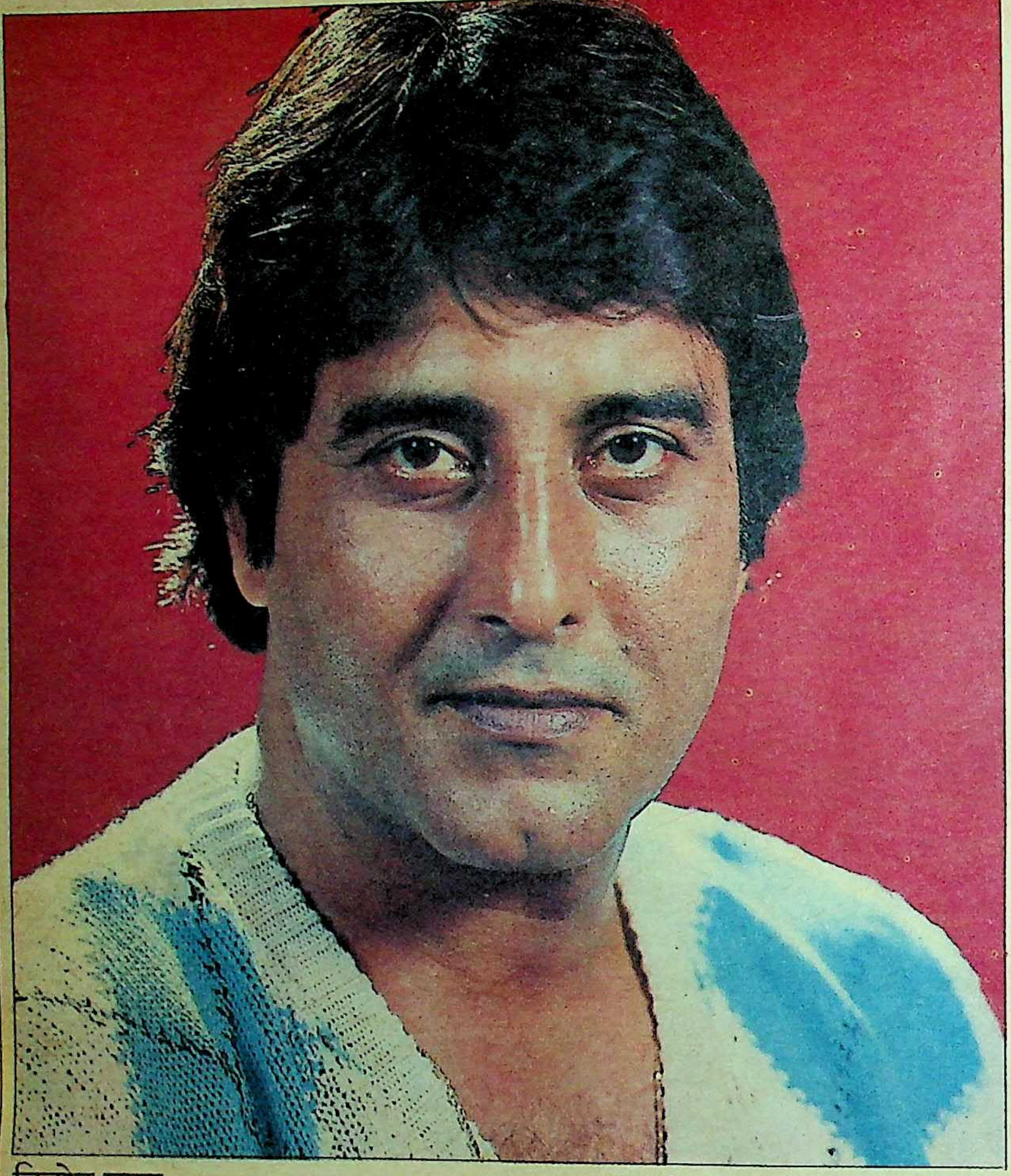

विनोद खन्ना

छाया : प्रदीप चन्द्र

वापसी के बाद

'इंसाफ', 'सत्यमेव जयते' फिल्म की व्यावसायिक सफलता ने न केवल विनोद खन्ना के पांव फिल्म जगत में पुनः जमा दिये हैं, बल्कि फिल्म वितरकों में उनकी फिल्मों को मुंहमांगी कीमत पर खरीदने की होड़-सी मच गयी है। धर्मेंद्र-विनोद खन्ना की जोड़ी वाली फिल्मों को पिछले वर्ष जहां २५ लाख रुपए भी प्रति वितरण क्षेत्र खरीदार नहीं मिल रहे थे, वहीं अब उन्हीं फिल्मों को ५० लाख रुपए प्रति वितरण क्षेत्र से भी अधिक में खरीदने के इच्छुक वितरक निर्माताओं के चक्कर लगा रहे हैं। इन दो फिल्मों की सफलता ने विनोद खन्ना का बाजारभाव रातोंरात साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया है। फिल्म जगत के छह दशक के इतिहास में ऐसी आपाधापी पहली बार हुई है। विनोद खन्ना अचानक इतने कीमती कैसे हो गये? क्या वह 'नंबर वन' स्टारों के लिए खतरा बन सकते हैं?

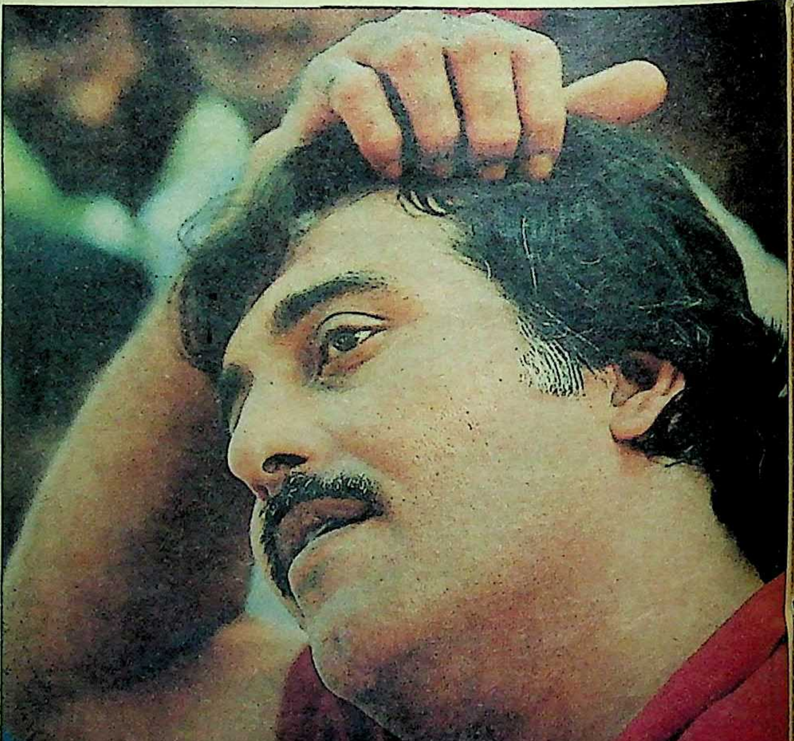

पिछले वर्ष जब विनोद खन्ना ने धुरंधर एवं बाक्स आफिस फार्मूला के गणितज्ञ माने जानेवाले निर्माता-निर्देशक राज खोसला की फिल्म 'नकाब' की शूटिंग कर फिल्म छोड़ दी थी और नितिन मनमोहन जैसे नये निर्देशक की फिल्म को तमाम 'शूटिंग डेट्स' मुहैया कर दी थी, तब अधिकांश फिल्मवालों ने मान लिया था कि आचार्य रजनीश की शरण से 'मुक्ति' पा लेने के बावजूद विनोद खन्ना उनके 'ट्रांस' से मुक्त नहीं हो पाये हैं और अब भी उन्हें 'आध्यात्मिक झटके' लगते हैं, जिनसे निजात पाने के लिए उन्हें 'पिल्स' लेनी पड़ रही हैं।

ओरेगांव में रजनीश पुराण के समापन के बाद वापस बंबई लौटे विनोद की कमोबेश यही स्थिति थी। कई महीनों तक वह लोगों से भागे-भागे फिरते रहे थे, अपने घनिष्ठ मित्रों से भी कन्नी काटते रहे, जबकि समूची फिल्म इंडस्ट्री उन्हें अमिताभ बच्चन का विकल्प मान कर अपनी फिल्मों के अनुबंधों के गुलदस्ते सजा कर उनके पीछे दौड़ती रही। इन्हीं लोगों में थे राज खोसला, जिन्होंने 'मेरा गांव मेरा देश' में धर्मेंद्र के साथ तब नये-नये आये विनोद खन्ना को काम देकर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। इसके बाद राज खोसला की कई फिल्मों में विनोद ने काम किया और उन्हें हमेशा अपना 'गुरु' मानते रहे। इसीलिए ओरेगांव से वापसी के बाद राज खोसला ने जब विनोद को पुनः स्थापित करने के लिए एक महीने में शूटिंग पूरी करने की योजना बनायी तो विनोद ने पूरी डेट्स उन्हें दे दीं। लेकिन सेट पर आकर भी विनोद अपने आपको शूटिंग के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाते। ठीक से वह न तो संवाद बोल पाते और न ही रोल के अनुसार 'एक्सप्रेशंस' दे पाते। वह घंटों मेकअप रूम में आंखें बंद किये बैठे रहते। उधर, फिल्म इंडस्ट्री के बाजार में यह हवा तेजी से गर्म हो गयी कि विनोद की अभिनय-प्रतिभा 'रजनीशी ध्यान' के दौर में विलुप्त हो चुकी है और वह कभी भी उस मोह से उबर नहीं सकेंगे। फलतः विनोद खन्ना पर

रुपए लगाने के लिए तैयार फायनेंसरों, वितरकों एवं प्रदर्शकों ने अपने हाथ धीरे-धीरे ढीले करने शुरू कर दिये। काफी प्रयासों के बावजूद जब राज खोसला विनोद खन्ना से इच्छानुसार काम नहीं ले सके, तो उन्हें अनुबंध की शर्तों से मुक्त कर दिया और उनकी जगह ऋषि कपूर को लेकर नये सिरे से फिल्म 'नकाब' की शूटिंग शुरू कर दी।

इस प्रकरण से फिल्म निर्माताओं के आगे बढ़े पांव रुक गये थे। अगर विनोद खन्ना के इर्द-गिर्द उनके जिगरी फिल्म निर्माता-निर्देशकों का सुरक्षा-कवच न होता, तो पिछले ही वर्ष विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो रातोंरात गुमनामी के अंधेरे में खो गये होते। लेकिन उनके मित्र-फिल्मकार उनकी मानसिक अवस्था से परिचित थे, इसलिए वे उनकी मानसिक रूप से वापसी के लिए इंतजार करने को भी तैयार थे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी, राज खोसला के अनुबंध से मुक्त होते ही विनोद खन्ना ने तेजी से काम शुरू कर दिया।

दरअसल, विनोद खन्ना राज खोसला की फिल्म 'नकाब' में काम नहीं करना चाहते थे। नकाब नायिका-प्रधान फिल्म थी और विनोद खन्ना महसूस कर रहे थे कि वह रोमांटिक एवं संवेदनशील भूमिकाओं के बल पर स्थापित नहीं हो सकते। पहले भी ऐसी भूमिकाओं में वह सफल नहीं हो सके थे। इमेज का यह कायाकल्प भारी पड़ सकता है, उनकी वापसी के लिए। अब अपने 'गुरु' राज खोसला से वह साफ-साफ मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जानबूझ कर कैमरे के सामने या 'नकाब' के सेट पर वह असामान्य होने का नाटक करने लगे। राज खोसला की अनुभवी आंखों ने इसे भांप लिया। चूंकि फिल्म में उनके लाखों रुपए लग चुके थे, इसलिए वह किसी भी तरह से फिल्म को पूरी कर लेना चाहते थे। लेकिन, उन्हें बड़ी जल्दी महसूस हो गया कि उनके सेट पर 'असामान्य हो गया शिष्य' दूसरे फिल्म निर्माता के सेट पर पहुंचते ही 'सामान्य' हो जाता है। उसके साथ वह 'नकाब' ताजिंदगी पूरी नहीं कर सकते थे, अतः लाखों रुपए का नुकसान उठाकर भी उन्होंने अपने 'शिष्य' को मुक्त कर देना तथा उस पर शूट किये गये सारे दृश्य 'स्क्रैप' कर देना आवश्यक समझा।

"नहीं, विनी (विनोद खन्ना) ने 'नकाब' के सेट पर असामान्य होने का कोई नाटक नहीं किया था"—विनोद खन्ना के एक घनिष्ठ दोस्त तथा फिल्म निर्माता ने 'माया' को बतलाया, "दरअसल, वह बंबई आने के बाद एक नयी समस्या को लेकर उलझ गये थे। वह समस्या थी, गीतांजलि भाभी की। विनी के (स्व०) स्मिता एवं फिर शबाना के साथ रिश्तों को लेकर उन्हें सख्त नाराजगी थी। उन पारिवारिक तनावों से मुक्ति पाने के लिए ही रीना राय की सलाह पर वह भगवान (रजनीश) की शरण में गये थे और फिर पूरी तरह से वहीं अनुरक्त हो गये। विनी ओरेगांव में रहकर भी बच्चों से फोन पर बात करता था। उन्हें वहां बुलाता था, लेकिन उससे सख्त नाराज गीतांजलि भाभी ने शायद उससे दुबारा संपर्क रखना जरूरी नहीं समझा। इसलिए विनी के बंबई वापस लौटने पर वह आस्ट्रेलिया चली गयीं। विनी बंबई आते ही भगवान (रजनीश) की भारत वापसी की व्यवस्था में जुटा रहा, फिर बच्चों से मिलने के लिए बेचैन हो गया। मानसिक रूप से परेशान विनी राज खोसला की फिल्म के सेट पर सहज नहीं हो पाता था।"

छाया : चित्रा वर्मा

> जिन फिल्मी पिस्तौल और बंदूकों को विनोद खन्ना बंबई छोड़कर ओरेगांव चला गया था, वहां से वापस लौटने के बाद उन्हें उसने पुनः उठा लिया, क्योंकि उसे अमिताभ बच्चन का विकल्प बनना था।

बहरहाल, जिन फिल्मी पिस्तौल और बंदूकों को विनोद खन्ना बंबई छोड़कर ओरेगांव चला गया था, वहां से वापस लौटने के बाद उन्हें उसने पुनः उठा लिया, क्योंकि उसे अमिताभ बच्चन का विकल्प बनना था। उसे यह भी पता था कि दर्शक अब टेसुए बहानेवाले चाकलेटी हीरो को नहीं, बल्कि सैकड़ों खूंख्वारों का मिनटों में सफाया करनेवाले निहत्थे नायकों को पसंद करते हैं और फिल्म वितरक ऐसी ही फिल्मों को सबसे पहले खरीदते हैं। इस 'फिल्मी सत्य-बोध' से वाकिफ विनोद खन्ना ने फिल्मों की शूटिंग डेट की प्लानिंग नये सिरे से की और इसका परिणाम थीं, 'इंसाफ' तथा 'सत्यमेव जयते' की उसकी भूमिकाएं।

विनोद खन्ना ने 'नकाब' के साथ-साथ राज सिप्पी की 'सत्यमेव जयते' तथा नितिन मनमोहन की 'इंसाफ' भी साइन की थी। राज सिप्पी से उनकी दोस्ती गुलजार की फिल्म 'अचानक' के समय से थी। तब वह गुलजार के सहायक थे। जब राज सिप्पी ने अपनी पहली फिल्म 'झंकार' का निर्देशन किया, तो अमिताभ बच्चन, जो उनके पिता एन०सी० सिप्पी की अधिकांश फिल्मों ('आनंद' से लेकर 'आलाप' तक) में नायक की भूमिकाएं निभाते रहे, के बजाय विनोद खन्ना को लिया और 'झंकार' बाक्स आफिस पर सुपर हिट हुई। नितिन मनमोहन के पिता चरित्र अभिनेता (स्व०) मनमोहन ने विनोद खन्ना को सुनील दत्त से 'मन का मीत' में काम देने की सिफारिश की थी। विनोद खन्ना के विदेश-प्रवास के दौरान जब मनमोहन की मृत्यु हुई, तो उन्होंने ट्रंककाल कर नितिन को अपनी संवेदनाएं प्रकट की थीं और आश्वासन दिया था कि जब भी नितिन को उनकी सहायता की जरूरत होगी, तो वह आंख मूंद कर उनके पास दौड़े आयेंगे।

"विनी जब बंबई आये तो मैंने उनसे अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव रखा तो वह तुरंत राजी हो गये।" नितिन मनमोहन ने 'माया' को बतलाया, "के० के० शुक्ला की एक कहानी उन्हें पसंद आ गयी। निर्देशक मुकुल आनंद की 'सल्तनत' के कारण उन दिनों काफी चर्चा थी। मेरे पास वे साइन भी थे। 'सागर' में डिंपल के अभिनय को विनी ने काफी पसंद भी किया था और उसे फोन कर बधाई भी दी थी। इस तरह 'इंसाफ' के प्रोजेक्ट को बनाने में न केवल विनी ने मेरी मदद की, बल्कि हर तरह का सहयोग भी दिया और फिल्म को ओवर बजट बनने तथा फालतू खर्चों को रोकने के बारे में वह निर्देश भी देते रहे।"

सफलता का बीजगणित : 'इंसाफ' के तुरंत बाद राज सिप्पी की 'सत्यमेव जयते' प्रदर्शित हुई। इन दोनों फिल्मों की बाक्स आफिस सफलता ने विनोद खन्ना के फिल्मी कैरियर का गणित ही जैसे बदल दिया। 'इंसाफ' और 'सत्यमेव जयते' के निर्माताओं को मुंहमांगी कीमत देने में कतरा रहे वितरकों में, इन दोनों फिल्मों के हिट होने पर विनोद की दूसरी निर्मित, निर्माणाधीन और घोषित—सभी तरह की फिल्मों को बढ़े हुए भाव पर खरीदने के लिए होड़-सी मच गयी। इत्तिफाक से 'लोहा' तथा दूसरी फिल्मों की व्यावसायिक सफलता से इसी वर्ष वापस लौटे धर्मेन्द्र के साथ जितनी फिल्में विनोद खन्ना ने साइन कीं, वे सभी ४५ से ५० लाख रुपए प्रति टेरीटरी (वितरण क्षेत्र) के रेशियो पर, शूटिंग शुरू हुए बिना ही, बिक गयीं, जबकि पिछले वर्ष ऐसी फिल्मों को २५ लाख रुपए के रेशियो पर भी खरीदार नहीं मिल पा रहे थे।

निर्माता सलीम की १९८७ की सबसे बड़े बजट की फिल्म 'बंटवारा' (धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मोहसिन खान, डिंपल कपाड़िया, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लों आदि) को खरीदने के लिए वितरकों ने अंधाधुंध कीमतें पेश कीं। निर्माता के कार्यालय में वितरकों-प्रदर्शकों का मेला-सा लग गया था। सभी चाहते थे कि निर्माता सलीम, जिन्होंने 'बंटवारा' की टेरीटरी अपेक्षाकृत कम कीमत पर, जिन वितरकों को पहले बेच दी थी, उनसे वितरण अधिकार लेकर मनमानी कीमत पर उन्हें बेच दें। लेकिन, वचनबद्ध सलीम ने इसे 'व्यावसायिक बेइमानी' कह कर उन्हें 'ओब्लाइज' करने से मना कर दिया। विनोद खन्ना पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने निर्माता को उनकी मनचाही सारी डेटें एक साथ दे दीं ताकि समय के भीतर फिल्म पूरी हो जाये।

बढ़ता क्रेज : वितरकों-प्रदर्शकों में विनोद खन्ना

के बढ़ते 'क्रेज' और उनकी फिल्मों के मुंहमांगे ऑफर को देखते हुए दक्षिण के एक फिल्म निर्माता ने विनोद खन्ना की फिल्म 'प्राइज' (१० लाख रुपए) को तिगुने से अधिक (३२ लाख रुपए) बढ़ाकर एक फिल्म साइन कर ली। एक और निर्माता ने इसमें तीन लाख और जोड़कर उनके सामने अपनी फिल्म का ऑफर रख दिया। फिल्म इंडस्ट्री के पिछले छह दशकों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, जबकि किसी आउट हो गये सितारे के 'प्राइज' को एकबारगी इतना बढ़ा दिया जाये। श्रीदेवी और धर्मेंद्र को भी, कई सुपर हिट फिल्में इस वर्ष देने पर भी, यह 'सौभाग्य' नहीं मिला था, जो विनोद खन्ना को मिला। अमिताभ बच्चन से लेकर श्रीदेवी ने अपनी कीमतें फिल्मों की व्यावसायिक सफलता को देखते हुए धीरे-धीरे बढ़ायी थीं, लेकिन अपनी ही सफलता से हत्प्रभ विनोद खन्ना को अपनी 'प्राइज' के पुनर्मूल्यांकन का मौका फिल्म निर्माताओं ने न देकर खुद अपनी बोली बढ़ा दी। सलीम के बाद रमेश सिप्पी (शोले, सागर, बुनियाद आदि) द्वारा विनोद को अपनी नयी फिल्म 'जिंदगी' के लिए साइन करते ही फिल्म जगत के बाजार क्षेत्र में जैसे हंगामा-सा बरपा हो गया। विनोद खन्ना के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अमिताभ की एक मजबूत दीवाल ढहा दी थी।

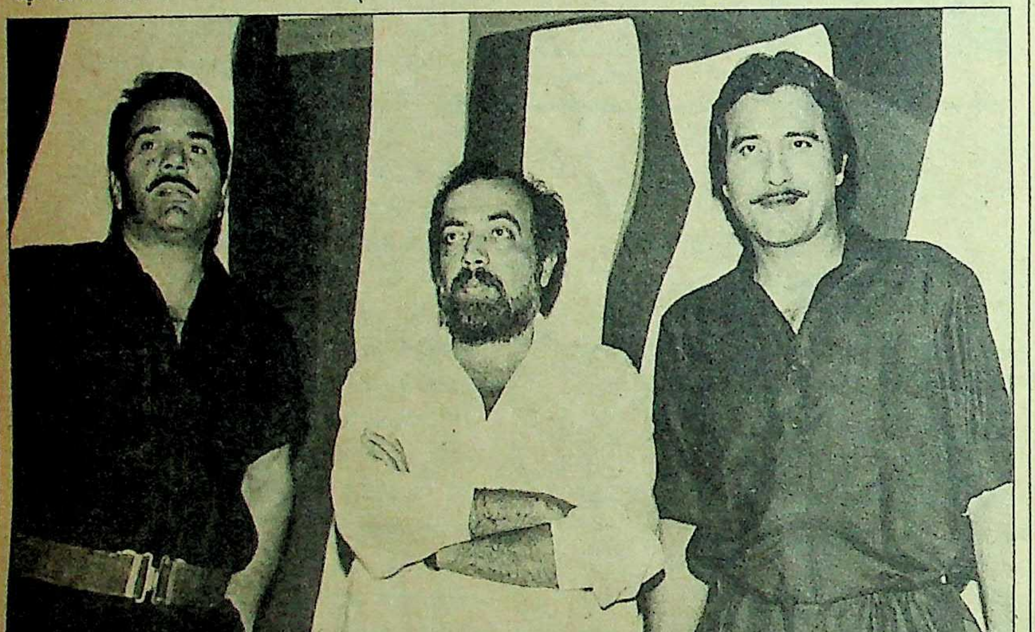

क्या जोड़ी फिर हिट होगी ? : 'मेरा गांव मेरा देश' के बाद फिल्म 'बंटवारा' में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना। बीच में निर्देशक जे०पी० दत्ता

छाया : एस० राजेश

दक्षिण के निर्माताओं की दिनोंदिन बढ़ती बोली ने बंबई के फिल्म निर्माताओं को संकट में डाल दिया है, क्योंकि अगर वे विनोद खन्ना को दिन दूने बढ़ते 'प्राइज' पर अनुबंधित करते हैं, तो फिल्म निर्माण के लिए फायनेंसरों से भारी ब्याज पर धन का जुगाड़ करने, फिर डेट्स लेने में काफी अरसा बीत जायेगा और इस बीच कुछ फिल्में, अगर दुर्भाग्य से फ्लाप हो गयीं और विनोद खन्ना का 'मार्केट' कम हो गया तो उन्हें अपनी दूकानें बंद कर देनी पड़ेंगी। (बंबई तथा दक्षिण में फिल्मी अर्थ व्यवस्था के इसी अंतराल के कारण दक्षिण के निर्माता जहां एक वर्ष में फिल्म पूरी कर लेते हैं, वहीं बंबई के फिल्म निर्माता को ढाई-तीन वर्ष लग जाते हैं। एक वर्ष में फिल्म पूरी कर लेने के कारण अगर फिल्म बाक्स आफिस पर असफल भी हो गयी तो निर्माता को आर्थिक नुकसान नहीं होता, लेकिन ढाई-तीन वर्ष में ओवर बजट हो गयी बंबइया फिल्म के निर्माता को भारी कर्ज में डूब जाना पड़ता है।)

विनोद को १९८६ में साइन करने वाले अधिकांश फिल्म निर्माता उसके दोस्त हैं। वे इस खतरे और इसके हादसे के परिणाम को पूरी तरह आंक कर चिंतित हैं कि अगर एक बार विनोद दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के भंवर-जाल में, जीतेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की तरह, फंस गये तो उनकी फिल्में अधर में ही लटक जायेंगी और उन्हें पूरी करने के लिए विनोद खन्ना चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पायेंगे।

"नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है"—फिल्म 'बंटवारा' के निर्देशक तथा विनोद के मित्र जे०पी० दत्ता ने 'माया' को बतलाया, "हमने तीन शिड्यूल में १५-१५ दिन की विनोद और अन्य सितारों की डेट्स नक्की कर ली है और इसमें न तो उलट-फेर हमारी तरफ से संभव है, और न ही विनोद की तरफ से। विनोद की एक विशेषता है कि जब वह किसी बात को 'कमिट' कर लेता है, तो उसे पूरा करने के लिए अंत तक जुटा रहता है। मैंने 'गुलामी' की शुरुआत विनोद खन्ना को लेकर की थी। विनोद को इसकी कहानी भी काफी पसंद थी, लेकिन १९८० में जब उसने अंततः 'ओरेगांव' जाने का निश्चय कर लिया तो एक दिन खुद धरमजी के पास गया। उन्हें 'गुलामी' की कहानी सुनायी और फिल्म में अपनी जगह उन्हें काम कर लेने के लिए राजी कर लिया। ऐसा भला कौन करता है? फिर धरमजी की ग्रेटनेस यह कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि मेरा 'डायरेक्टोरियल कैरियर' कुछ भी नहीं है, 'गुलामी' में काम करना मंजूर कर लिया। इसीलिए जब मुझे 'बंटवारा' के निर्देशन का ऑफर मिला तो मैंने पहला और आखिरी चुनाव धर्मेंद्र एवं विनोद खन्ना का ही किया।" (जे०पी० दत्ता को, जब वह रणधीर कपूर के सहायक थे, तो उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो विनोद खन्ना ने ही 'सरहद' और 'गुलामी' का निर्देशन दिलवाया था। 'सरहद' तो बन नहीं पायी, लेकिन 'गुलामी' के हिट होते ही, वह प्रथम श्रेणी के निर्देशक बन गये।)

अमिताभ भी डरे : विनोद की वापसी को अमिताभ बच्चन का विकल्प माना गया था, लेकिन 'इंसाफ' एवं 'सत्यमेव जयते' की व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ अमिताभ के जोरशोर से फिल्मों में शूटिंग शुरू कर देने की घटना ने स्टारडम व्यवसाय के समीकरण को बदल दिया है। अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा देने से पहले हर सप्ताह एक फिल्म की दर से लगभग एक दर्जन फिल्में अनुबंधित कर ली थीं। अमिताभ के व्यवहार से नाखुश प्रकाश मेहरा ने पिछले वर्ष उनकी जगह विनोद खन्ना को लेकर फिल्में बनाने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि 'मुकद्दर का सिकंदर', 'हेराफेरी' आदि कई फिल्मों में विनोद खन्ना ने उनके साथ काम किया था। मनमोहन देसाई भी विनोद को अमिताभ का विकल्प में मान थे। विनोद ने उनके साथ 'अमर-अकबर-अंथोनी' आदि फिल्में की थीं। विनोद खन्ना की कई फिल्मों के निर्माता नादियाडवाला ने भी आगे की फिल्में विनोद के साथ करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन इन तीनों की तरह और भी कई परिणाम का जायजा लेने के बाद ही विनोद के साथ फिल्में शुरू करना चाहते थे। इस खतरे को भांप कर अमिताभ ने इन सारे निर्माताओं से खुद तोड़े हुए संबंधों को खुद ही सुधार कर उनकी सभी फिल्मों में काम करने की मंजूरी दे दी।

"लेकिन विनी को कोई खतरा नहीं है"—'सत्यमेव जयते' के निर्देशक राज सिप्पी का कहना था, "विनी के पास प्रभावशाली कहानियोंवाली ढेर सारी फिल्में हैं और हर फिल्म उसके अभिनय की छाप छोड़ने में सक्षम होगी। कुछ दिनों पहले फिल्म इंडस्ट्री के सामने यह खतरा जरूर था कि अगर एक-के-बाद-एक सितारों की फिल्में पिटती रहीं, तो न तो कलाकार ही स्थापित हो सकेंगे और न ही फिल्म निर्माता, वितरक, प्रदर्शक अपने को आर्थिक संकट के दौर से उबार सकेंगे। काफी दिनों के बाद पुनः एक बार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा मौका आया है, जब एक साथ कई 'सेलेबुल आर्टिस्ट' उभर आये हैं और उनकी फिल्में बाजार में बिना नानुच के बिक रही हैं।

लेकिन, इस मौके ने डेढ़ दशक पूर्व जैसी स्थिति पुनः पैदा कर दी है और बहुसितारीय फिल्मों का जमाना लौटा दिया है। ऐसे में, विनोद खन्ना को सोचना होगा कि वह 'अमर-अकबर-अंथोनी' युग की तरह तीन-तीन नायकोंवाली फिल्मों के चमकते सितारे बने रहें या 'अचानक' जैसी फिल्मों में कामकर उस स्थान को भर सकें, जो संजीव कुमार के निधन से खाली पड़ गया है। अमिताभ बच्चन के जोर-शोर से वापसी के बाद फिलहाल उनके विकल्प की बात तो खतम हो गयी है। अब तो सिर्फ बराबरी की लड़ाई है और अमिताभ से नाराज रमेश सिप्पी (शोले, बुनियाद), जे०पी० दत्ता, महेश भट्ट, राज सिप्पी जैसे स्टार निर्माता-निर्देशकों की एक लंबी कतार विनोद खन्ना के पीछे उनकी रहनुमाई के लिए खड़ी है।

—रवींद्र श्रीवास्तव

सलीम अली

पक्षियों से उनका आत्मिक रिश्ता था

नौ वर्ष की उम्र में परिंदों का शिकार करनेवाले सलीम अली की जिंदगी में एक हादसा हुआ—जैसा बालमीकि की जिंदगी में हुआ था। सलीम अली की जिंदगी की धारा भी बालमीकि की जिंदगी की तरह बदल गयी। परिंदों का शिकार करनेवाले सलीम अली पशु-पक्षियों के न केवल प्रेमी बन गये, बल्कि समूचे भारत में घूम-घूम कर पक्षियों के बारे में अभूतपूर्व जानकारियां एकत्र करते रहे। वन्य-जीवन के रक्षार्थ ताजिंदगी जीने वाले सलीम अली की सारी जिंदगी यायावरी में बीती—न अपना कोई घर-द्वार बनाया न संपत्ति खड़ी की। प्रस्तुत है सलीम अली के मित्र एवं वरिष्ठ पत्रकार शलिल घोष के रोचक संस्मरण तथा रवींद्र श्रीवास्तव द्वारा सलीम अली के संघर्षों एवं उपलब्धियों का लेखा-जोखा :

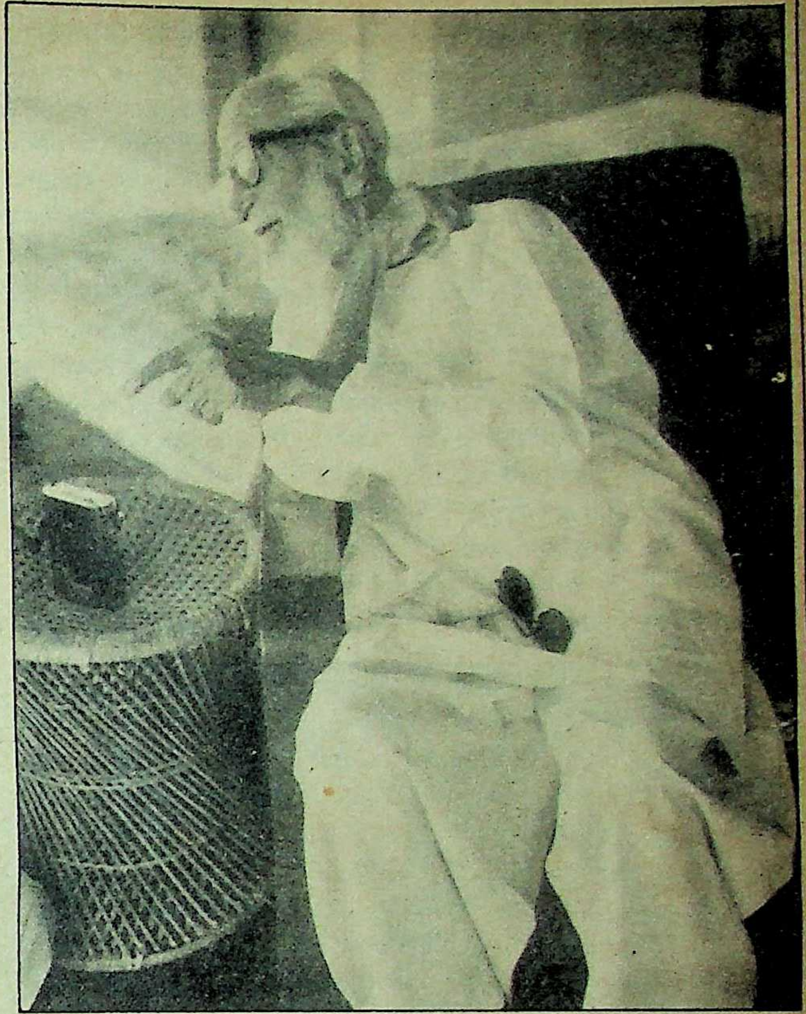

दोस्ती और दुश्मनी दोनों दिल पर गहरा जख्म दे जाती है, मैं दुश्मनी की नहीं दोस्ती की बात कर रहा हूं। ३९ वर्षों की दोस्ती या साथ कहिए, मामूली बात नहीं होती। साथ इसलिए कि वह मुझसे उम्र में लगभग दोगुने थे, दोस्ती इसलिए कि वह मुझे अपना दोस्त मानते थे और दोस्ती के नाते बहुत कुछ कह भी जाते थे। पाक दिल, खुले मन के इंसान बिरला ही मिलते हैं, इसलिए दोस्ती का इतना लंबा काल भी बिरला ही हो पाता है और वह भी तब, जब एक पक्ष लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के आसमान छूता जाता है और दूसरा पक्ष जमीन पर खड़ा दूसरों की उपलब्धियों का गुणगान अखबारों-पत्रिकाओं के जरिये कर सारी दुनिया तक पहुंचाता है।

प्रथम पक्ष थे सलीम अली, दूसरा पक्ष था मैं लेखक-पत्रकार। सलीम अली की सही व्याख्या के लिए पिछले ३७ वर्षों में मुझे (बल्कि सभी को) एक भी शब्द नहीं मिला। उन्हें महर्षि कहूं, कर्मयोगी कहूं या प्राण-पुरुष! और जब मैं ऐसे शब्दों की चर्चा उनके सामने करता तो वह हमेशा मजाकिया मूड में आ जाते—"भई, तुम कम-से-कम महानता का खिताब मत दो। लोगों ने मुझे बेकार ही महान पक्षी-प्रेमी, नेचुरल हिस्ट्री का महान संरक्षक बना दिया है। पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा के बारे में मेरा अपना नजरिया है। कोई भी व्यक्ति किसी पशु या पक्षी को शूट कर देने का अधिकार भला कैसे रखता है या इस बात को सपने में सोच भी कैसे सकता है? हां, पशु-पक्षियों की जनसंख्या अगर इस हद तक सीमातिक्रमण कर जाती कि उस पर नियंत्रर संभव नहीं हो पाता, तो अलग बात थी। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं कि उनकी हत्या कर उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाये।"

इस हिसाब से तो दादा पशु-पक्षियों की नहीं आदमियों की जनसंख्या नियंत्रण की सीमा को पार करके खतरे के चिन्ह को भी पार कर गयी है" मेरी इस बात पर सलीम अली के झुर्रियों-भरे चेहरे पर बच्चों की शैतानी जैसी चमक कौंध आयी थी और उनका लहजा और भी मजाकिया हो उठा था—"तब तो जरूर कुछ इंसानों को शूट कर दिया जाना चाहिए। क्यों है न?" फिर अचानक ही वह गंभीर हो जैसे खुद से बात करने लगे थे—"हम जब किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो मारने का भला अधिकार कैसे रखते हैं..."

हमारे पौराणिक ग्रंथों में उस शिकारी बाल्मीकि का जिक्र है जिसे किसी निरीह को मारने में हिचक नहीं होती थी और वही बाल्मीकि एक घटना के बाद, मानवता के महानतम पुजारी बन बैठे थे। और जब मैंने उनका जिक्र सलीम अली से किया तो फिर उनके चेहरे पर वही शैतानी भरी मुस्कराहट छा गयी "तो अब तुम मेरी तुलना उस महान महर्षि और फिर उसके बाद क्रौंच-वध की घटना से करना चाहोगे, है न?"

क्रौंच-वध जैसी घटना : हां, सलीम अली की जिंदगी में भी क्रौंच-वध जैसी एक घटना घटी थी। उन्होंने एक बार खुद ही यह घटना सुनायी थी—"मैं तब ९ या १० वर्ष का रहा होऊंगा। मेरे मामू (अमीरुद्दीन तैयबजी) उस जमाने के मशहूर शिकारी थे, उनका निशाना अचूक होता था। उनके पास ऐसी-ऐसी बंदूकों का जखीरा था, जितना किसी अंग्रेज शिकारी के पास भी उस समय नहीं होता था। मामू ने मुझे ५००-शॉट की डेजी एयरगन लाकर दी। मेरे दूसरे भाईयों के पास भी एयरगनें थीं, जिनसे वे परिंदों का शिकार किया करते थे। शिकार के लिए छुट्टियों में हमारा परिवार चेंबूर जाया करता था। चेंबूर उन दिनों भारत का आज जैसा सर्वाधिक प्रदूषणयुक्त उपनगर नहीं था, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और झरनों से भरा एक खूबसूरत सैरगाह था। एक दिन हम सब भाई जब चेंबूर के जंगल में जाकर परिंदों का शिकार कर रहे थे, मेरी एयरगन के निशाने का शिकार होकर एक गौरैया जमीन पर आ गिरी। हमने उसे दौड़ कर उठाया तो चौंक उठे—वह आम गौरैयों से थोड़ा अलग थी, उसके कंठ पर पीले रंग के चकत्ते से फैले हुए थे। उसे हलाल करने के पहले मामू जान के पास ले गये, तो वह भी उसे देखकर चौंके कि इस तरह की गौरैया उन्होंने न तो पहले कभी देखी थी और न ही उसके बारे में कभी सुना था। मेरी जिज्ञासा और कौतूहल को देखकर वह बहुत खुश हुए और मुझे मिलार्ड साहब के पास भेजा।"

वाल्टर सैम्युल मिलार्ड बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसकी स्थापना १८८३ में हुई थी, के मानव सचिव थे और पशु-पक्षियों के प्रति उन्हें काफी रुचि थी। उनके मामू भी सोसाइटी के सदस्य मिलार्ड के दोस्त थे। मिलार्ड को, जिन्होंने सलीम अली की जिंदगी की धारा ही जैसे बदल दी थी, वह ताजिंदगी अपना आदर्श-पुरुष

मानते रहे थे। उस दिन की घटना उन्होंने सुनायी थी—"मैं उनके बंगले पर काफी डरते-डरते पहुंचा था। वह प्रथम बड़े अंग्रेज अफसर थे, जिससे मैं रूबरू हुआ था। ये वे दिन थे (१९०६-७) जब अंग्रेज लोग भारतीयों से बहुत कम रूबरू होते थे। मिलार्ड साहब फार्बेस स्ट्रीट और अपोलो स्ट्रीट के चौराहे पर बने उस बंगले में रहते थे जहां पहले बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहा करते थे। उनके बंगले पर खाकी वर्दीधारी सिपाहियों का पहरा रहता था, काफी पूछताछ के बाद मुझ 'काले' (भारतीय) को उनके बंगले में घुसने की इजाजत मिली। मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा जहां दीवारों पर लटके हुए शिकार किये गये जानवरों के सिर, खालें आदि उनके शिकारी होने का अहसास करा रहे थे। ऊपर की मंजिल पर शो-केसों में सीशेल्स, तितलियां, चिड़ियों के अंडे आदि भरे पड़े थे और लकड़ी की दीवारों पर चीते, शेर आदि आदमखोरों के सिर, खाल तथा अस्थिपंजर टंगे हुए थे। गोरे साहबों के बारे में सुनी हुई हैरतअंगेज कहानियों तथा इन चीजों ने मेरे भीतर वहां पहुंचने से पहले ही पैठी दहशत और हतोत्साह को सौगुना बढ़ा दिया। लेकिन गंजे सिर वाले मिलार्ड साहब एकदम विपरीत निकले। मामू के पत्र को पढ़कर और मेरे शिकार उस गौरैया को देखकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपायी, नाश्ते की प्लेट मंगवायी। उन्होंने इस गौरैये का परीक्षण कर न केवल उस बारे में मुझे पूरी जानकारी दी, बल्कि भारत में पाये जानेवाले पक्षियों के अपने संग्रहालय को भी दिखलाया, पशु-पक्षियों से संबंधित कई पुस्तकें अपने पुस्तकालय से निकालकर पढ़ने के लिए दीं और वहां आने का आमंत्रण भी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें परिंदों के बारे में शौक है, तो उनका शिकार करने के बजाय उन्हें पालना और फिर उनका 'आब्जर्वेशन' करना शुरू करो। तुम यहां समय निकालकर आया करो, मैं तुम्हें इस बारे में पूरी ट्रेनिंग दूंगा। फिर उन्होंने दूसरे कमरे में बैठे एक अंग्रेज युवक नार्मन मोईड किन्नियेर से तवारुख करवाया। यही नार्मन साहब बाद में ब्रिटिश म्यूजियम में पक्षी विभाग के इंचार्ज फिर म्यूजियम के डायरेक्टर नियुक्त हुए और उन्हें 'सर' की उपाधि मिली।" (नार्मन के निर्देश पर एस०एच० प्रेटर तथा पी०एफ० गोम्स ने सलीम को पक्षियों के रखरखाव से संबंधित पूरी ट्रेनिंग दी।)

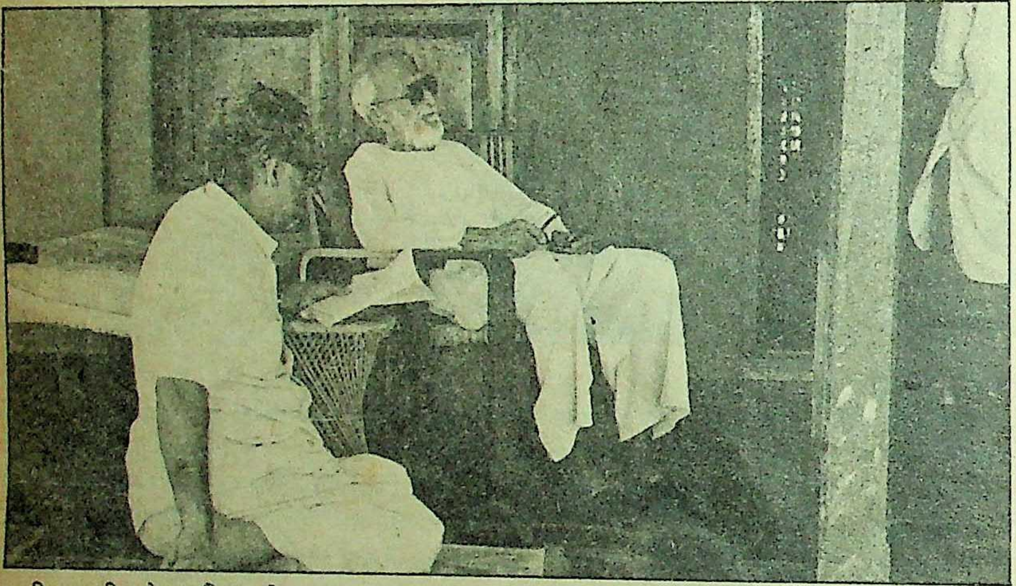

सलीम अली और शलिल घोष

सलीम के घर पर क्राफर्ड मार्केट से परिंदे लाकर बांस के बने दड़बों में रखे जाते थे और उन्हें हलाल कर पकाया जाता था। मिलार्ड के मिलने के बाद उनके जीवन में एक नयी तब्दीली यह आयी कि जेब खर्च के लिए प्रतिमाह मिलनेवाले दो रुपयों से वह तरह-तरह के परिंदे क्राफर्ड मार्केट से खरीद कर ले आते और उन्हें अलग से पालते। इस तरह उनके पास अच्छा-खासा संग्रह जमा हो गया था, लेकिन परेशानी भी आये दिन तब तक बनी रहती जब पिंजरों में रखे परिंदों की मौत हो जाती। नार्मन की सलाह पर वह परिंदों को कुछ समय रख उसका परीक्षण कर फिर पिंजरों से आजाद कर देते। लेकिन शिकार भी उनका चलता रहता।

परिस्थितियों का योगदान : सलीम ने ९ वर्ष की उम्र में, मामू द्वारा दिये गये डेजी एयरगन से जब सात दिनों में ८ मादा गौरैयों का शिकार कर डाला, तो हर किसी ने उनकी पीठ थपथपायी थी। उसी समय उनके मन में यह भावना कहीं अनजाने ही घर कर गयी थी कि शिकार मादा परिंदे का नहीं, नर का करना चाहिए। संभवतः इसके पीछे उनका बचपन रहा हो जब उन्हें मां-बाप के प्यार से मरहूम होना पड़ा था।

"पशु-पक्षियों के प्रति मेरे रुझान में हमेशा परिस्थितियों ने काफी योगदान किया।" एक बार सलीम ने मुझे बतलाया था, "१९१० में, जब मैं १४ वर्ष का था, मुझे क्रानिक सिर-दर्द की शिकायत शुरू हुई, तो डाक्टरों ने हवा-पानी बदलने की सलाह दी, तो मुझे बड़े भाई-भाभी (हामिद एवं शरीफा) के पास सिंध-हैदराबाद भेज दिया गया। हामिद भाई के साथ अकसर मैं शिकार पर जाता या पक्षीगाहों की तरफ अकेले निकल जाता और उनके बारे में जानकारियां एकत्र किया करता। एक बार हम लोग टांडो शिकार के लिए गये। तब एक रात हमने हेली कामेट के दर्शन किये। उस रात शिविर के बाहर हेली कामेट के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हर एक व्यक्ति की जबान पर एक बात थी—'इस बार तो हम हेली कामेट का दर्शन करेंगे, लेकिन ७६-७७ वर्ष बाद जब यह फिर पृथ्वी के निकट दिखलायी पड़ेगा तो पता नहीं हममें से कौन जिंदा रहेगा।' मैंने झट उत्त दिया, 'अगली बार भी मैं जरूर हेली कामेट देखूंगा।' त कुछ लोग मेरी बात को बाल-मुद्धि मान कर हंस पड़े लेकिन ७६ वर्ष बाद हेली को मैंने पुनः देखा तो उस रा की बात याद आ गयी और सप्ताहों तक जेहन में घटना समायी रही। हैदराबाद में मेरा एक वर्ष ज खराब हुआ था, लेकिन पशुओं-पक्षियों को निकट जानने का काफी मौका मिला।"

चार वर्ष बाद परिस्थितियों ने उनकी जिंदगी एक और नाटक खेला। एस०एस०सी० की परीक्षा बाद वह जीव-विज्ञान (विशेष रूप से ओर्रियोलॉजी लेना चाहते थे, ताकि बड़े होकर वह जीव-विज्ञानी सकें। इसके लिए पशु-पक्षियों से संबंधित पुस्तकों हमेशा अध्ययन करते रहते थे। लेकिन शिक्षा नीतियों कारण उस समय ऐसा संभव नहीं था। गणित-अलजब में मन नहीं लगता था और अकसर इन कक्षाओं से गु मार जाते। इत्तिफाक से तभी बर्मा से बड़े भाई जबीर पत्र आया। जिनका बर्मा में खुद का कारोबार था १९१४ में, १८ वर्ष की उम्र में, सलीम अली तेवा (बर्मा) पहुंच गये और भाई के कारोबार में हाथ बंटा लगे। सलीम हर शनिवार को दोपहर को दुकान बंद हो पर सुदूर क्षेत्रों में निकल जाते और पक्षियों आब्जर्वेशन करते। उनकी समस्या थी—बर्मी पक्षियों बारे में जान न पाने की विवशता, लेकिन इसका हल उन्होंने शीघ्र ही ढूंढ़ लिया। इत्तिफाक से उन मुलाकात डिवीजनल फारेस्ट आफिसर जे०सी० हा वुड से हो गयी जो न केवल बर्मी एवं आसपास के पक्षि के विशेषज्ञ थे, बल्कि उनके पास परिंदों से संबंधि बहुमूल्य संग्रह भी था।

जब वह बर्मा में थे, तभी १९१८ में उन्हें बं बुलवाकर उनका विवाह दिसंबर महीने में तहमीना करा दिया गया। विवाह के बाद सलीम तहमीना लेकर वापस तेवाय चले गये। १९२३ में जबीर ने अप व्यवसाय बर्मा से समेट लिया तो सलीम बंबई लौट आ इन नौ वर्षों में सलीम ने पक्षियों का काफी अध्यय किया। जब वह विवाह के लिए बंबई आये तो एक तक बंबई में रुक कर डावर्स कालेज आफ काम कार्मशियल एवं एकाउंटेंसी का फार्मल कोर्स करने निश्चय किया। इसी बीच सेंट जेवियर कालेज के विज्ञान विभाग के निदेशक रेवरेंड फादर ब्लेडर को सलीम की जीव विज्ञानी बनकर पशु-पक्षियों के काम करने की रुचि के बारे में पता चला तो वह खुद खुद मदद के लिए आगे आ गये। फलतः उन्हें उसी जीव विज्ञान में बी०एस०सी० (तब बी०ए० आनर्स करने की अनुमति मिल गयी। प्रो० जाल पी० मुल्लन उन्हें काफी मदद की। बाद में दोनों दोस्त बन गये

जीव विज्ञान में बी०ए० आनर्स की डिग्री बर्मा वापस लौटने के बाद काम आयी और उन्हें बाम्बे नेचुर हिस्ट्री सोसाइटी में काम मिल गया। उसी समय उन्हों पक्षियों पर अध्ययन कर एक शोधपरक लेख 'बर्ड्स आ बाम्बे एंड सालसेटे' लिखी जो नेचुरल सोसाइटी पत्रिका में बाद में छपी। वह हर रविवार को सुबह तड़ उठकर बंबई के सालसेटे क्षेत्र (पवई, तुलसी व विहा लेक, ट्रांबे हिल्स, मुलुंट, विक्रौली, भांडुप, घोड़बंद भयंदर आदि) पहुंचकर पक्षियों को पकड़ते। कभी-क

उन्हें वहां पर प्रेटर, मैककान तता जेकब (प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम के सचिव) भी आते और उन्हीं के साथ परिंदों को पकड़ते। ये सभी स्थान उन दिनों खूबसूरत पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे हुए थे।

दो हादसे: इसी बीच तहमीना को भी बाम्बे प्रेसिडेंसी वुमेन कौंसिल में सचिव पद पर पार्ट टाइम काम मिल गया। इसी दौरान नियति ने दो हादसे किये। उनकी चर्चा चलते ही सलीम अली कुछ क्षण के लिए खामोश हो गये थे—"पता नहीं ये दोनों हादसे मेरे लिए लाभप्रद थे या हानिकारक, लेकिन मैंने तो उन्हें लाभप्रद ही मानकर संतोष कर लिया था। जब मैं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में काम कर रहा था तब जूलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में ओरॅिथोलॉजिस्ट के पद के लिए मैंने आवेदन किया, लेकिन सारी विशेषताएं होने के बावजूद इस पद के लिए मेरा चुनाव इसलिए नहीं हो सका कि मेरे पास विश्वविद्यालय की निर्धारित डिग्री नहीं थी। मैं ओरॅिथोलॉजिस्ट बनना चाहता था, लेकिन डिग्री न होने के कारण नहीं बन सका और इसका मलाल काफी दिनों तक बना रहा। दूसरी घटना थी—चेंबूर स्थित सरकारी बंगला जिसे सरकार बेच रही थी। उस बंगले के विशालकाय कंपाउंड में तरह-तरह के पेड़-पौधे लगे हुए थे। तहमीना के पिता कमरुद्दीन साहब यह बंगला तहमीना के लिए खरीदना चाहते थे। क्योंकि सारे भाई-बहनों में एक मैं ही था, जिसके पास अपना रहने के लिए एक छोटा-सा भी फ्लैट नहीं था। उन्होंने इसके लिए सरकार को दरख्वास्त भी भेजी। लेकिन इत्तिफाक देखिए कि सरकारी मंजूरी जिस दिन हमें मिली, ठीक एक दिन पहले अंकल (श्वसुर) की मौत हो चुकी थी। अब उस बंगले को खरीदने की कूबत हममें नहीं थी। और इस तरह मेरा और तहमीना का एक ऐसे बंगले में रहने का सपना धरा-का-धरा रह गया।"

१६३० के आसपास सलीम ने १७०० रुपए में नयी बेबी आस्टिन कार खरीद ली। तहमीना प्रख्यात कथाकार जेन आस्टेन की प्रशंसक थी, इसलिए कार का नाम जेन रख दिया और खुद उसकी देखरेख करती। कार हो जाने से उनके आने-जाने की समस्या हल हो गयी, क्योंकि उस समय आज की तरह बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। कार से एक फायदा सलीम को यह हुआ कि वह पक्षियों को पकड़ने के लिए हर रविवार को बंबई से बाहर पूना, नासिक, औरंगाबाद, शोलापुर आदि पशु-पक्षीबहुल क्षेत्रों तक जाने लगे। एक बार उनकी कार भीमा नदी के दलदल में फंस गयी और दोनों नदी में जलसमाधि लेने से बाल-बाल बचे।

संघर्ष-पर-संघर्ष: बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में काम करने के पहले, बर्मा से बंबई पहुंचते ही कुछ समय तक उन्हें एन०डी० फतेहअली एंड कं० में १५० रुपए वेतन पर हेडक्लर्क का काम मिल गया। कुछ ही दिनों बाद कंपनी की हालत खस्ता होने पर वेतन घटाकर १०० रुपए कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद नौकरी भी छूट गयी, तो उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें अदन आने का आमंत्रण दिया, लेकिन इस बार उन्होंने बंबई में ही संघर्ष करने का निश्चय किया। इसी बीच बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चरर की नियुक्ति के लिए सरकार को राजी कराने में सफल हो गयी। रेवरेंड फादर ब्लैटर तथा म्यूजियम के क्यूरेयर प्रेटर के साथ उनका परिचय काम आया और दो वर्षों के लिए इस पद पर उनकी नियुक्ति हो गयी।

सलीम अली की पत्नी तहमीना

लेकिन सलीम अली पक्षियों के बारे में और भी प्रशिक्षण एवं शोध करना चाहते थे, भारत में इस तरह की व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में नहीं थी। मजबूरी में उन्हें तरह-तरह की नौकरियां करनी पड़ रही थीं। इस बारे में ब्रिटिश म्यूजियम तथा बर्लिन युनिवर्सिटी जूलाजिकल म्यूजियम से उन्होंने खतोकिताबत जारी रखी। ब्रिटिश म्यूजियम ने बहुत निराशाजनक उत्तर दिया, लेकिन बर्लिन युनिवर्सिटी के प्रोफेसर इर्विन स्ट्रैसमैन के हार्दिकता-भरे पत्र ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उन्होंने बर्लिन जाने का निश्चय कर लिया।

प्रो० स्ट्रैसमैन ने टैक्सोनॉमी में प्रैक्टिकल के लिए सलीम को सुझाव दिया कि वह भारतीय पक्षियों पर एक शोध ग्रंथ लिखें। उसके लिए प्रो० स्ट्रैसमैन उनका गाइड बनने के लिए भी तैयार थे। "मेरे लिए उस समय यह बहुत बड़ा आफर था—सम्माननीय आफर" सलीम अली ने एक बार बतलाया था—"और मैं तुरंत राजी हो गया

प्रो० स्ट्रैसमैन साहब बहुत ही दरियादिल, सीधे, मिलनसार और हर क्षण मदद करने वाले इंसान थे। मैं आज भी उन्हें अपना गुरु मानता हूं और ताजिंदगी मानता रहूंगा। बर्लिन से वापस आने के बाद भी जब मुझे टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी या जियोग्रॉफी में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, वह हमेशा मेरी सहायता करते रहे। प्रो० स्ट्रैसमैन के साथ-साथ मैं किन्नियर साहब का भी यहां जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे शुरुआत में मार्गदर्शन कर 'वह' बनने की प्रेरणा दी जो आज 'मैं' हूं या बनना चाहता था। बर्लिन जूआलाजिकल म्यूजियम में काम करते समय मेरी मुलाकरत बर्नहार्ड रेंश से हुई। उन्होंने सुंदा आयलैंड के बहुमूल्य पक्षियों और पशुओं का एक संग्रह बना रखा था और इन विषयों से संबंधित कई पहलुओं के विशेषज्ञ थे। हम दोनों में तो घनिष्ठ दोस्ती हो ही गयी, तहमीना की भी उनकी खूबसूरत पत्नी से खूब छनने लगी और जब हम दोनों अपने काम में मशगूल होते, वे दोनों अपना समय साथ-साथ काटतीं। वहीं पर मेरी मुलाकात एक और प्रतिभाशाली युवक अर्न्स्ट मेइर से हुई। वह न्यू गायना क्षेत्र में पक्षियों का विस्तृत अध्ययन तथा विशिष्ट पक्षियों का संग्रह कर बर्लिन लौटे थे और हमारे साथ काम कर रहे थे। हम तीनों मिलकर एक साथ और कभी-कभी अलग काम करते और एक-दूसरे को अपने-अपने कामों की बिना किसी भेदभाव के पूरी जानकारी देते। मेइर विश्वयुद्ध छिड़ने के पहले न्यूयार्क चले गये और अमरीकन म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए काम करने लगे, फिर हावर्ड यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान के प्रोफेसर हो गये। जब मैं न्यूयार्क गया तो पुनः मेरी वहां पर उनसे मुलाकात हुई।"

१६३० की शुरुआत में सलीम अली वापस बंबई लौट आये। अब फिर वह बेरोजगार थे। बम्बई के निकट स्थित किहिम (अलीबाग) में रह कर पक्षियों के संग्रह में वह अपना खाली समय बिताने लगे। उन्होंने बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जिन क्षेत्रों में पक्षियों के बारे में सर्वेक्षण नहीं हुआ है वहां वह वालंटियर के रूप में काम करना चाहेंगे। सोसाइटी को सिर्फ आवश्यक खर्चों का ही बंदोबस्त करना होगा। हैदराबाद स्टेट में कुछ भी काम इस सिलसिले में नहीं हुआ था। निजाम प्रशासन में उच्च पद पर काम करनेवाले अधिकांश अधिकारी ब्रिटिश आई०सी०एस० थे और सोसाइटी के सदस्य थे। निजाम के वित्तमंत्री सर अकबर हैदरी को सलीम अली की उपलब्धियों के बारे में पता था। जब सोसाइटी ने सलीम अली के प्रस्ताव पर निजाम प्रशासन से बातचीत की तो प्रस्ताव तुरंत मंजूर हो गया और हैदराबाद स्टेट ओरॅिथोलॉजिकल सर्वे का गठन हुआ। इसके लिए ३ हजार रुपए प्रतिमाह का अनुदान भी मंजूर हो गया। सर्वे के काम के लिए तीन महीने की अवधि निर्धारित की गयी जो सलीम अली के अनुरोध पर दो महीने और बढ़ा दी गयी।

हैदराबाद में काम के लिए उन्हें सुदूर क्षेत्रों में बैलगाड़ियों से ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पार करना पड़ता। तहमीना हर समय उनके साथ रहती। सलीम के साथ अधिकांश रास्ता वह भी सामानों से लदी बैलगाड़ियों के पीछे-पीछे पैदल ही चलती। हैदराबाद में पांच महीनों में (अक्तूबर से दिसंबर, १६३१ तथा मार्च-अप्रैल, १६३२) उन्होंने पक्षियों के सर्वेक्षण का काम कर लिया, तो फिर उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उठ खड़ी हुई। परिस्थितियों ने पुनः उनका साथ दिया।

हैदराबाद में श्रीमती नंदी से सलीम अली की अच्छी दोस्ती हो गयी थी। अप्रैल,' ३२ में काम पूरा हो जाने के बाद उन्होंने उनसे अपने कोटागिरी हिल्स (नीलगिरि हिल्स क्षेत्र) में छुट्टियां बिताने का आग्रह किया। वहां पर उनका एक खूबसूरत बंगला 'मोन आबरी' था। सलीम अली तहमीना के साथ कोटागिरी पहुंच गये। अभी तक उन्होंने दक्षिण भारत के जंगलों में पक्षियों का मुआयना नहीं किया था। कोटागिरि में उन्हें तरह-तरह के पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूरा मौका मिला। वहां पर उनकी मुलाकात राल्फ मॉरिस (कॉफी प्लांटर) से हुई। वह शिकारी भी थे और

वन्य जीव रक्षा के लिए काम भी करते थे। १९५३ में जब जम्मू-कश्मीर सरकार ने बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से डाचीगाम तथा दूसरे सैंक्चुरीज में वन्यजीवन के सर्वेक्षण के लिए दो-तीन व्यक्तियों की टीम भेजने का आग्रह किया, तो राल्फ मारिस के साथ-साथ सलीम अली को भी नियुक्त किया गया।

सलीम जब नीलगिरि में थे तभी उन्हें बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक पत्र मिला जिसमें त्रावणकोर-कोचीन में पक्षियों-जीवों के सर्वेक्षण की योजना को मंजूरी दी गयी थी और उन्हें तुरंत वहां पहुंचकर काम प्रारंभ करने के लिए अनुरोध किया गया था। सलीम अली १९३० से १९५० के बीस वर्षों की अवधि में किये गये पक्षी सर्वेक्षण अभियानों में सर्वाधिक उपयोगी-फलोत्पादक त्रावणकोर-कोचीन के अभियान को मानते रहे। उन्होंने दक्षिण की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं, वनों एवं नदियों का काफी रोचक वर्णन अपनी पुस्तक 'द बर्ड्स आफ केरल' में किया है।

त्रावणकोर-कोचीन का काम खतम हो जाने पर बेरोजगारी जब पुनः सामने आ खड़ी हुई, तो उन्हें लगा इस तरह की बनजारा जिंदगी भला कितने दिन चल पायेगी। न घर-व्दार, न सामाजिक-पारिवारिक जिंदगी और न ही कोई स्थायी नौकरी-दोस्तों-रिश्तेदारों के घरों पर रहना, अस्थायी सर्वेक्षण अभियानों को पूरा कर फिर बेरोजगार हो जाना। बड़े भाई हमीद, जो इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर होकर मसूरी में बस गये थे, ने उन्हें देहरादून आने की सलाह दी।

तहमीना के साथ वह १९३४ में देहरादून आ गये और पांच वर्षों तक वहीं रहे। बर्मा के बाद देहरादून पहली जगह थी, जहां वह टिक कर रहे। उन दिनों की चर्चा करते हुए अकसर सलीम अली की आंखें सजल हो जाया करती थीं— "वे पांच वर्ष हम दोनों की जिंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हे थे, जो इतनी जल्दी बीत गये कि उसका अहसास ही नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत, महत्वपूर्ण चीज भी खुशियों के उन स्वर्णिम दिनों में ही खो दी थी।"

और वह खूबसूरत चीज थी— तहमीना, सलीम की जीवन संगिनी, जो सलीम के ४३वें वसंत में ही उनका संग छोड़ कर खुदा को प्यारी हो गयी। शल्य-क्रिया के बाद तहमीना के खून में जहर फैल गया और जुलाई १९३९ में उनकी अस्पताल में ही मौत हो गयी।

तहमीना की मौत के बाद सलीम एकदम एकाकी हो गये तो कामू तथा अन्य बहनों-भाइयों एवं रिश्तेदारों ने उन्हें अपने पास आ कर रहने के लिए जोर दिया, ताकि तहमीना की मौत के कारण आये खालीपन का असर उनकी सेहत पर न पड़ने पाये। लेकिन सलीम अली खुद को अपने काम में अधिक-से अधिक मश्रूफ रखना चाहते थे।

तहमीना के इंतकाल के बाद सलीम पुनः रेगिस्तानी पशु-पक्षियों का सर्वेक्षण करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच उन्हें अफगानिस्तान जाने का मौका मिल गया। १९३५ में, जब वह देहरादून में थे, हग व्हिसलर ने उन्हें इंग्लैंड से लिखा कि 'पक्षी-विशेषज्ञ कर्नल आर० मेइनर्तझागेन पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए अफगानिस्तान जाने वाले हैं, उन्हें एक विशिष्ट सहयोगी की जरूरत है। अगर तुम तैयार हो तो उनसे बात करूं? सलीम अली तैयार हो गये।

अफगानिस्तान के सुदूर क्षेत्रों में उन्हें कई विशिष्ट पक्षियों को देखने-पकड़ने और अध्ययन करने का मौका मिला। इनमें से एक पक्षी था-कोमान फीजांत, जो उन्हें दाछोरी में मिला था। इसके अलावा स्नोकाक, सीसी पार्टरिज, रेडलेग्ड फालकन, लेसर केसट्राल, रोजी पैस्टार जैसे विशिष्ट चिड़ियों को पकड़ा। अफ्रीका से पूर्वी एशिया में विचरनेवाले ये पक्षी हर वर्ष ४ मई के बाद हजारों की संख्या में दानाछोरी तथा दूसरे क्षेत्रों में पहुंचते थे।

अफगानिस्तान से लौटने के बाद कुछ समय तक बेरोजगार रहने के कारण १९४५ में उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। देहरादून-प्रवास के समय वह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं आदि पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा कर वहां पक्षियों-जानवरों के बारे में काफी काम कर चुके थे। उनका कहना था कि सुदूर पहाड़ों पर एक बार जाने से पूरा अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के पक्षियों का भोजन, रहन-सहन तथा आदतें मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं इसलिए उनका अध्ययन क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और हिमालय की यात्राएं कीं। इन पूर्वी पहाड़ी रेंजों की यात्रा के बाद उन्होंने पश्चिम तिब्बत पहाड़ी रेंज की यात्रा की, जो और भी कठिन तथा दुरूह थी। यहां एक विशेष मौसम में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही बारहेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी आते थे। १७ हजार फुट से भी अधिक ऊंचाई की यह दुरूह यात्रा सलीम अली ने अपनी सहयोगी प्रीतम सेन (जो अमरीका में पक्षियों पर शोध कर रहे थे) तथा एक कुली खेम सिंह के साथ की थी।

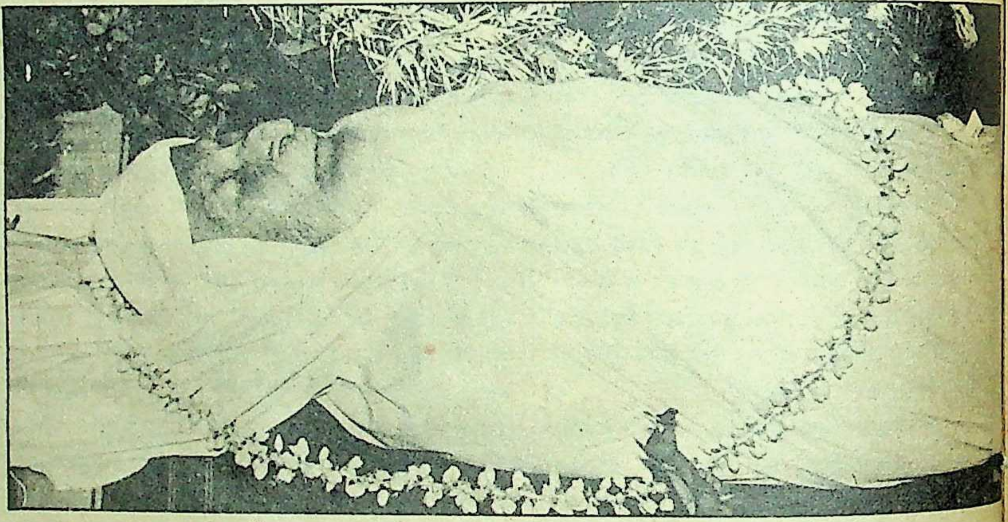

चिरनिद्रा में सलीम अली

१९५७ में क्यासानूर जंगल में रहनेवाले बंदरों एवं ग्रामीणों को अचानक इंसेफेलिटिस रोग (बंदर-रोग के नाम से ज्ञात) लग गया और जब बहुत से लोग इसके शिकार हो गये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ। इस रोग के कीटाणु रूस और भारतीय पक्षियों के आवागमन से फैला था। १९५९ में जब सलीम अली जिनेवा में आयोजित पक्षी रोगों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये तो उन्होंने इस गंभीर समस्या के मूल कारणों की तरफ पक्षी विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कराया और कच्छ तथा उत्तर पश्चिमी भारत में पक्षियों के आगमन का विशेष रूप से अध्ययन कराने की योजना भी पेश की, क्योंकि विभिन्न देशों से इन क्षेत्रों में समय-समय पर आनेवाले पक्षी अपने-अपने देशों से यह रोग ले आते थे, जो स्थानीय पक्षियों-पशुओं को लग जाते थे और उनकी अकाल मौत हो जाती थी। १९२९ में हेलिगोलैंड के ओरिंथोलॉजिकल आब्जरवेटरी में अध्ययन के दौरान भी उन्होंने इन वाइरस रोगों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उस समय इस पर विशे ध्यान नहीं दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी एक लंबे अरसे तक खामोश रहा।

भरतपुर में काम करते समय सलीम अली को पत चला कि साहनी तथा भिरशीकर जनजातियों के लो पक्षियों को पकड़ने में माहिर होते हैं। इसके पह अध्ययन के लिए पक्षियों को उन्हें शूट करना पड़ता था उन्होंने तुरंत उन लोगों से मुलाकात कर पक्षियों क पकड़ने और उनके गले में रिंग पहनाने की व्यवस्था की सलीम अली के प्रयास से केवलादेव घना झील के विशाल क्षेत्र में पहले वाटर बर्ड सैंक्चुअरी, फिर नेशनल पा बना। १९६४ तक उन्होंने भारत के अधिकांश पक्षीबहु क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया।

सलीम अली ने 'द बुक ऑफ इंडियन बर्ड् (१९४१), 'द बर्ड्स ऑफ कच्छ' (१९४५), 'इंडि हिल बर्ड्स' (१९४९), 'बर्ड्स ऑफ त्रावणको कोचीन' (१९५३), 'बर्ड्स ऑफ सिक्किम' (१९६२ 'बर्ड्स ऑफ केरल' (१९६९), 'फील्ड गाइड टु द बर्ड् ऑफ ईस्टर्न हिमालयन', 'हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑ इंडिया ऐंड पाकिस्तान' (१९६८-७४) आदि क पुस्तकें लिखीं एवं इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडि नेचुरन हिस्ट्री आदि कई ग्रंथों के संपादन किये। एल फतेह अली के साथ मिल कर 'काम बर्ड्स' भी लिखी १९८५ में प्रकाशित उनकी आत्मकथा 'द फाल ऑ स्पैरो' विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में गिनी गयी। अपने ग्रंथों के हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं अनुवाद की योजना बना रहे थे ताकि पक्षियों के बारे अधिकाधिक जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके लेकिन उनकी मौत के कारण, साथ ही आर्थिक अभाव कारण भी, यह योजना मूर्त नहीं हो सकी थी।

■

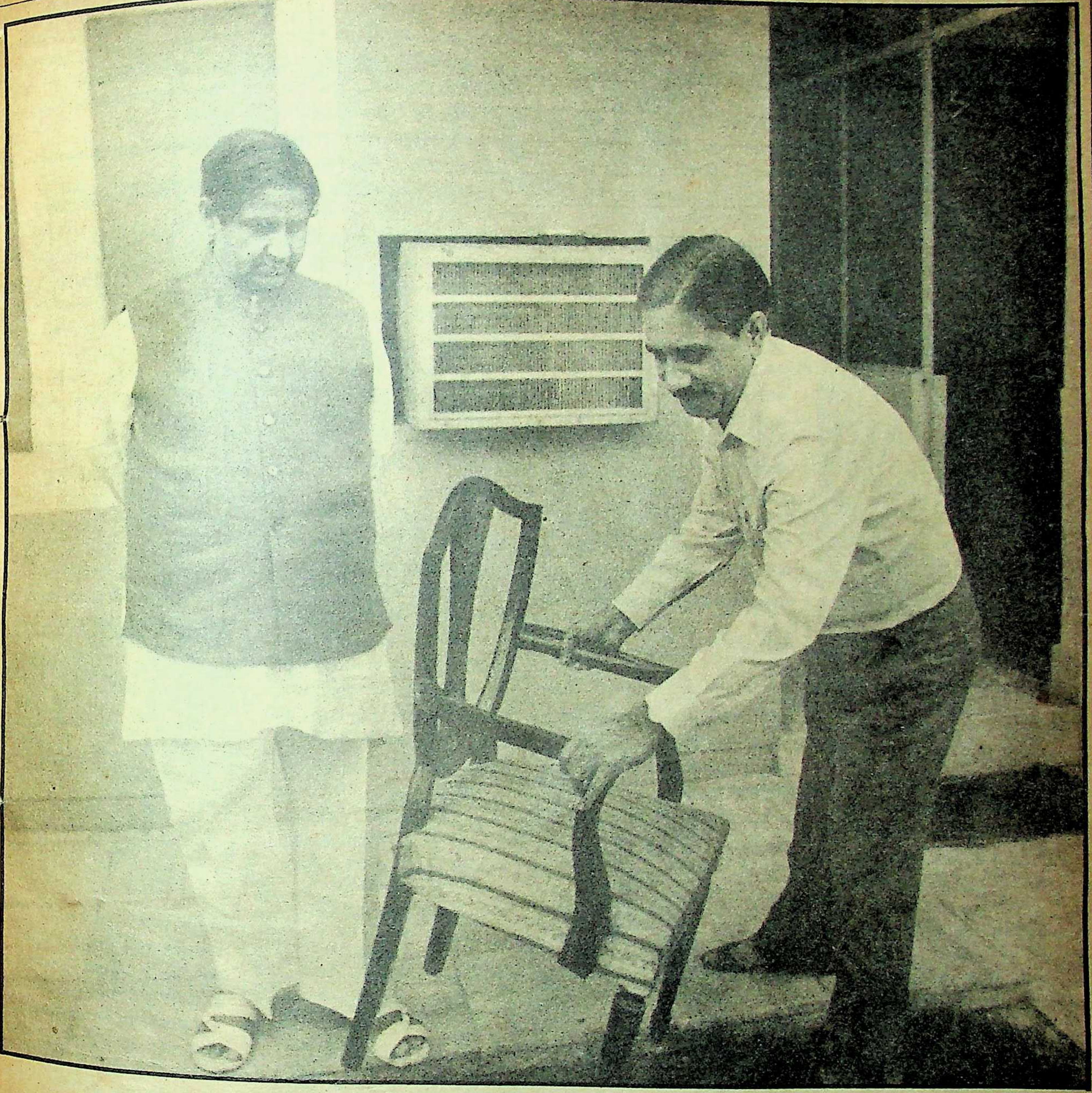

छाया :
फाल एस० गिरोटा

वह राजनेता ही क्या, जिसकी अर्जुन की तरह दृष्टि अपने लक्ष्य-यानी कुरसी पर न टिकी हो ! और भला वह राजनेता क्या खाकर राजनीति करेगा जो यही नहीं जानता कि दरबार में कौन ऐसा शूरमा है, जिसमें कुरसी खिसकाने और दिलाने का पराक्रम है ! इस मामले में अपने कल्पनाथ रायजी का कोई जवाब नहीं। एक जमाना था, जब कुरसी प्रदायक क्षमता वाले लोगों को वह बखूबी पहचानते थे, इसलिए किसी को कुरसी मिले या न मिले, उनके लिए एकाध कुरसी बचाकर रख ली जाती थी। पहचान अब भी है, लेकिन वह क्या करें ! इस दरबार में कुरसी दिलाऊ लोग ताश के पत्तों की तरह जल्दी-जल्दी फेंट दिये जाते हैं। लेकिन अपने राय साहब हार मानने-वाले शख्स नहीं हैं। भगवान ने उनको जबान दी है और उसे उन्होंने वफादारी के रेसकोर्स में लगाम तोड़ कर सरंपट दौड़ा रखा है। यह तो वक्त बतायेगा कि वह के०के० तिवारी की तरह कोई गच्चा खाते हैं या पार लगते हैं?

बेनजीर

बेनजीर नाम जबान पर आते ही एक बेमिसाल तस्वीर उभरती है। एक ऐसी युवानेत्री की जो पाकिस्तान के एक शासक परिवार में जन्मी और पिता भुट्टो की फांसी के बाद अपने वतन से सात वर्षों के लिए निर्वासित हो गयी। पर वतन से दूर रहकर भी, जिसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का झंडा उठाकर मौजूदा पाकिस्तान के शासक जिया-उल-हक की नींद उड़ा रखी थी और जब सात वर्षों की निर्वासित जिंदगी के बाद १० अप्रैल, १९८६ को पाकिस्तान लौटी, तो पाकिस्तान में बेनजीर छा गयी। दुबली-पतली, लंबे कद की बेनजीर जो पाकिस्तानी जनता की स्वतंत्रता और हक के लिए लड़ती रही हैं—अब वैवाहिक जिंदगी में कदम रखनेवाली हैं। पर यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि बेनजीर परिणय-सूत्र में बंध कर राजनीति छोड़ देंगी। जिसके पिता को फांसी लगी हो, जिसने निर्वासित जिंदगी जी हो, पाकिस्तान की जेलों में रही हो—उससे ऐसी अपेक्षा बेमानी है। बेनजीर खुद कहती हैं कि शादी से मेरे राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं राष्ट्रपति जिया-उल-हक को सत्ताच्युत करने के लिए अपना अभियान जारी रखूंगी। मेरे लिए शादी की तुलना में देश-हित सबसे ऊपर हैं। ३४ वर्षीय बेनजीर ऐसे व्यक्ति से शादी करने जा रही हैं, जिनसे उनका पूर्व में खास परिचय नहीं था। पाकिस्तान के एक धनी किसान तथा व्यापारी आसिफ जरदारी ने मुस्लिम रिवाज के अनुसार बेनजीर की मां बेगम नुसरत भुट्टो के सामने प्रस्ताव रखा और बेगम भुट्टो ने मंजूरी दे दी। इसी के बाद लंदन में आसिफ जरदारी के साथ बेनजीर की शादी की घोषणा कर दी गयी। इस घोषणा के बाद बेनजीर ने इस शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उनका कहना है कि जब मेरे देश के लोग बम विस्फोट में मारे जा रहे हों और देश में शोक का वातावरण हो, ऐसे समय में शादी नहीं कर सकती; शादी की घोषणा तो हो ही गयी है, बस इंतजार है तारीख का।

श्रीदेवी

एक कहावत है, लोकप्रियता सिर पर चढ़कर बोलती है। श्रीदेवी आज ऐसी ही कहावत के फ्रेम में है। दक्षिण की फिल्मों से लोकप्रियता का मृदंग बजानेवाली श्रीदेवी जब हिंदी फिल्मों में आयी, तो एक वर्ष के अंदर ही उसने हिंदी फिल्मों की 'नंबर वन' अभिनेत्री हो जाने का नगाड़ा बजा दिया। लोकप्रियता का रिकार्ड बनाते-बनाते श्रीदेवी आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री के रिकार्ड तक पहुंच गयी है। अमरीका से प्रकाशित महिला फिल्म पत्रिका 'होम जर्नल' द्वारा 'विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय महिलाओं और अभिनेत्रियों' के किये गये सर्वेक्षण में श्रीदेवी का नाम भी दर्ज है। सर्वेक्षण में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर, अमरीकी राष्ट्रपति की पत्नी नैंसी रीगन, फिलीपींस की प्रधानमंत्री कोरी एक्वीनो, अफ्रीका की प्रख्यात महिला नेता विनी मांडेला, फिल्म अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर, ब्रिगिता बारदोत, केथरीन हेपबर्न और 'वाशिंगटन पोस्ट' की प्रकाशक कैथेरीन ग्राहम लोकप्रियता में सर्वश्रेष्ठ हैं।

पांच वर्ष की उम्र में तेलुगु फिल्म 'थुनैवन' में बाल भूमिका और ११ वर्ष की उम्र में तेलुगु'फिल्म 'अनुरागुलु' की नायिका से फिल्मी जीवन शुरू करनेवाली श्रीदेवी आज हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी अभिनेत्री है। श्रीदेवी वह पहली फिल्म अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मी परदे पर अवतरित होने के एक वर्ष बाद ही 'नंबर वन' के सिंहासन पर विराजमान होकर आज तक ताज पहने हुए है।

विश्व की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेत्री का ताज पहनने के बाद श्रीदेवी शीघ्र ही अमरीका और ब्रिटेन की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोकप्रियता-सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान पानेवाली अन्य महिलाओं और अभिनेत्रियों से मिलना।

विश्वनाथन आनंद

उधर उत्तरी आयर लैंड में गीत सेठी ने बिलियर्ड्स का विश्वविजेता होने का खिताब जीता और इधर फिलीपींस में विश्वनाथ आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन का खिताब जीतकर भारत के खेल प्रेमियों को दोहरी खुशी दे दी।

तमिलनाडु के १७ वर्षीय आनं यह खिताब जीतनेवाले एशिया के पहले खिलाड़ी हैं। आनंद ने इस्राय के गाड रेचलिस को कड़े मुकाबले पराजित किया। इस जीत से आनंद ग्रेंड मास्टर खिताब पाने के और नजदीक पहुंच गये हैं। आनंद की इ

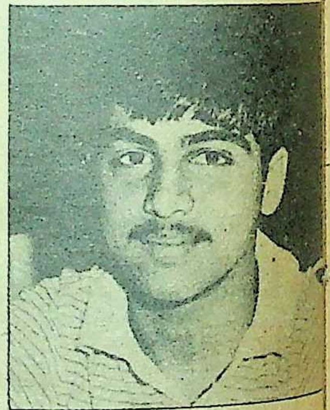

सफलता से २० वर्ष से कम उम्रवालों की इस प्रतियोगिता में यूरोपीय और अमरीकी खिलाड़ियों का वर्चस्व टूट गया।

प्रतियोगिता में भाग लेने के पू आनंद को विश्वास था कि वह इस बार विश्व जूनियर शतरंज का खिताब यदि नहीं जीत पाये, तो पह तीन में वह जरूर शामिल होंगे। प इरादा जब मजबूत हो और खेल मे साहस और संकल्प का समावेश हो, तो बड़ी उम्मीद पूरी होती है—इसे आनंद ने कर दिखाया है। इसके पहले आनंद लगातार तीन बार राष्ट्रीय शतरंज का खिताब जीत चु हैं।

—दिनेश दी

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

DUPLICATE

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

10|9|87

मनोहर कहानियाँ

भारत की सबसे ज्यादा बिकनेवाली हिन्दी पत्रिका
मनोहर कहानियाँ
प्रेम-कथा
पटना का रागिनी कांड प्रेम-विवाह की दुखद परिणति
एक फिल्म निर्देशक की पवित्र प्रेम-कथा
प्रेम-निवेदिता नरगिस
मूल्य-6.00

प्रेम-कथा विशेषांक

प्रमुख आकर्षण

० पटना का रागिनी कांड

रागिनी ने स्वेच्छा से
प्रेम-विवाह करके किस तरह दाम्पत्य
जीवन के नाम पर
नरक भोगा और अन्ततः
जल मरी...नारी की
सहनशीलता की करुण कथा
—आवरण कथा के रूप में प्रस्तुत

० प्रेम-निवेदिता नरगिस

वह नरगिस थी,
उसने प्रेम-निवेदन किया
और फिर धर्म, समाज तथा
परिवार का विरोध
झेलते हुए "निवेदिता" बन गयी...
एक मर्मस्पर्शी प्रेम-कहानी

० गुजरा हुआ तूफान

अभिजीत ने दया से प्यार
किया और शादी भी। फिर
हालात ने यों मोड़
लिये कि वह एक तूफान की तरह
गुजर गया। अब दया है
और दया की गोद में
दुधमुंहा बच्चा...एक प्रेम-कथा

० नसीब

एक ऐसी अभागी युवती
की व्यथा-कथा, जो दो विवाहों
के बाद आज समाज के
सामने प्रश्नचिह्न बनकर खड़ी है

अन्य आकर्षण

- नागपुर का बिल्कीस बानू कांड
- सालगिरह की रात
- निर्दोष किशोरियां और आतंक तेजाब का
- एक फिल्म निर्देशक की विलक्षण प्रेम-कथा

१ सितम्बर तक प्रकाश्य
मूल्य रु० ६/-

आज ही समाचार पत्र विक्रेताओं से प्राप्त करें

When you are searching Your interest areas in an English magazine....
....Take a look at PROBE INDIA

PROBE
ANTULAY Splitting the Cong
REKHA "I still need romance"
An Appeal to You
Abbas & Uma Vasudev
Reddy Report on Sexuality in Madras

If business, investment climate and the share market are the areas of your interest, Probe has some of the most investigated reports on the contemporary scene to share with you.

If it is the political scene, you will be more than satisfied with the objective reports from all around the country.

There is almost everything in Probe, you could look for-sports, cinema, media, focus on international scene, women, lifestyle, human interest and regional coverages.

And for your leisure you have the visual delight of photo-features.

Probe is an interesting and bold blend of topical coverage with an insight into the future, for we take a stand on controversial issues.

PROBE INDIA
Reporting with credibility that's seeded within.

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक १७

माया

१५ सितंबर, १९८७

यह अंक

आवरण कथा

२२

३१ अक्टूबर, १९८४ को राजीव गांधी को उनकी मां का उत्तराधिकारी बनाने में अरुण नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लेकिन आज वही अरुण नेहरू उन लोगों के साथ हैं जो राजीव का तख्ता उलटने में लगे हैं। आखिर यह नौबत क्यों आयी? क्या विद्रोह के मुख्य रणनीतिज्ञ अरुण नेहरू ही हैं?

संजय सिंह की बगावत

अमेठी के राजकुमार डा० संजय सिंह तो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अचानक राजीव गांधी के खिलाफ बगावत क्यों कर दी? ८४

बिहार

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या के पीछे कौन सी शक्तियां हैं? उनकी हत्या किन उद्देश्यों से दुष्प्रेरित हो कर की गयी? ४२

दिल्ली में दहशत

पंजाब में फैले आतंकवाद की काली छाया जब से दिल्ली पर मंडराने लगी है, तब से राजधानी की स्थिति क्या हो गयी है? ४६

राजस्थान

राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के खिलाफ छात्र और शिक्षक क्यों आंदोलनरत हैं? ५३

मध्य प्रदेश

अमिताभ बच्चन के ससुर, प्रसिद्ध पत्रकार एवं राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तरुण कुमार भादुड़ी पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं, क्या वे सही हैं? ६५

मुजफ्फरनगर रैली

नवोदित किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा आयोजित रैली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर कौन से विवाद उठ खड़े हुए हैं? ३६

दिल्ली दरबार : सूखा उत्सव ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
बेढब १३
साक्षात्कार : प्रणब मुखर्जी : मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी १४
देश : शिक्षक सड़क पर १८
आवरण कथा : अरुण नेहरू से साक्षात्कार ३०
प्रसंगवश : खरीदिए आई०ए०एस० दूल्हा तीस लाख में ३३
बिहार : जगन्नाथ मिश्र की वापसी? ४१
महाराष्ट्र : पुलिसिया चेहरा ५१
पश्चिम बंगाल : विकास कलकत्ता का या कालेधन का? ५८
मध्य प्रदेश : गैसपीड़ितों पर दोहरी मार ६१
फिल्म : श्याम बेनेगल का सरकारीकरण? ७२
व्यक्तित्व : सीमांत गांधी : एक अपराजेय योद्धा ७६
परदे के पीछे ८२
खेल : कपिल देव को एक मौका और ९१
फोटोफीचर ९३
कार्टून ९७
अर्थतंत्र : शेयरबाजार कब तक वीरान रहेगा? ९८
अर्थतंत्र : सूखा : अशुभ संकेत १००
अचानक १०३
लोग १०४

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
विशेष संवाददाता
दिल्ली: राहुल देव
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
दिल्ली: पुनीत टंडन
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक:
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा:
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५६६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २६६०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

मनोहर कहानियाँ

अतिरिक्तांक **दीपावली** विशेषांक

प्रमुख आकर्षण

नताशा

एक ऐसे परिवार की लड़की की
रोमांचक सत्यकथा,
जहां जायदाद के बंटवारे के भय से
लड़कियों को न केवल कुंवारी
रखा जाता था अपितु उन्हें मरने के लिए
विवश भी किया जाता था

दक्षा की उत्पीड़न कथा

एक ऐसी नारी की हृदय-विदारक व्यथा-कथा,
जिस पर ससुराल में
केवल इसलिए सितम ढाया गया
कि उसका बेरोजगार पिता
दहेज की पूरी रकम देने में असमर्थ था

बिहार का निराला वर मेला

मिथिला के गौरव और मैथिलियों की
निराली परम्पराओं से जुड़े सौराठ मेले की
रोचक कहानी

खुशियां फिर लौट आयीं

संयम और सहनशीलता की अग्नि-परीक्षा में
खरी उतरने वाली एक ऐसी नारी की मार्मिक
कहानी, जिसका पति अपनी मां के संबंध में
गलतफहमी के कारण औरतों पर
अविश्वास करने लगा था

१५ सितम्बर तक प्रकाश्य

मूल्य-५.००

सामंती शब्दों से परहेज करें !

आजकल सभी पत्र-पत्रिकाएं विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए 'राजा मांडा', 'राजा साहब' या 'कुंवर' आदि संबोधनों का प्रयोग कर रही हैं, आखिर क्यों ? 'राजा' उनका नाम तो नहीं है। फिर क्या यह पदवी इसलिए प्रयोग की जा रही है क्योंकि उनके पूर्वज कभी किसी रियासत के राजा थे। तो माफ कीजिएगा अब राजा-महाराजाओं का जमाना चुक गया है। अब तो बस प्रजा ही है। इस तरह से किसी व्यक्ति को सामंती शब्दों से सजा कर जनता को बहकाना ठीक नहीं है। बेहतर हो पत्र-पत्रिकाएं अपना नजरिया बदलकर जनता को सही रास्ता दिखायें। 'माया' जैसी ख्यातिलब्ध पत्रिका, को इसके लिए पहल करनी चाहिए। —मनोज कुमार द्विवेदी, अनूपपुर, जिला शहडोल (म०प्र०)

एक विकल्प

'माया' १५ अगस्त, '८७ अंक की आवरण कथा 'विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीतिक गतिविधियां राजीव गांधी के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं,' सचाई भरी है। इस बात को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि राजीव के बजाय आज राजा साहब की लहर जनता में जोर-शोर से व्याप्त है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है राजा साहब द्वारा संबोधित सभायें, जिनमें उन्हें जनता का अप्रत्याशित सहयोग एवं समर्थन मिल रहा है। राजा साहब इसलिए भी राजीव पर हावी हैं, क्योंकि कांग्रेस एवं राजीव के 'खास' नेता भी इस वक्त उनके साथ हैं। अगले ढाई साल में भी वी०पी० सिह राजीव की हर कमजोर नीति का राजनीतिक पैंतरेबाज़ियों से लाभ उठाने में नहीं चूकेंगे। 'बोफोर्स और पनडुब्बी सौदे,' 'स्विट्ज़रलैंड में जमा करोड़ों रुपए की भारतीय संपत्ति' आदि ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं जिन्हें माध्यम बनाकर ही वह राजीव गांधी को भारी चुनौती दे सके। परंतु यदि उपरोक्त सभी मुद्दों को स्पष्ट जांच कराकर राजीव खतम कर दें, तो शायद ही दूसरा कोई मजबूत राजनैतिक हथियार राजा साहब के पास रह जायेगा। एक

फर्क जे०पी० और वी०पी० का

'माया' अगस्त, '८७ प्रथम पढ़ा। वर्तमान राष्ट्रीय समस्याओं पर विस्तृत व सही जानकारी मिली। इधर पिछले कई अंकों से लगातार आपकी पत्रिका के साथ-साथ राष्ट्र की अन्य पत्र-पत्रिकाओं के आकर्षण कांग्रेस के विद्रोही विशेषत: विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं। उनके पक्ष विपक्ष मे लगातार छप रहा है और ज्यादातर उनके पक्ष में। साथ ही कुछ ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिससे यह लगे कि वह वास्तव में आज के जननायक हों, जिनमें जनता को राजीवजी की भ्रष्ट सरकार का विकल्प नजर आये। हो सकता है आज देश की बहुसंख्यक जनता भी इन खबरों की चकाचौंध में इसे सच मान रही हो। पर, जहां तक मेरे मत का प्रश्न है मैं आप सबों की राय से अलग विचार रखता हूं, खासकर इस बात पर तो मेरा विशेष विरोध है कि वी०पी० सिंह की तुलना जे०पी० से की जा रही है।

वी०पी० सिह का आज जो भी कदम व प्रयास है वह प्रधानमंत्री की कुरसी तक ही जा रहा है जो कि उनकी हाल की घोषणा 'मैं भविष्य में कोई पद नहीं लूंगा' के विपरीत है। फिर, वी०पी० सिंह ने अपने २० वर्षीय राजनीतिक जीवन में ऐसा कौन-सा कदम उठाया जिससे उन्हें जननायक कहा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका में वह विफल हुए, तो इस्तीफा दे दिया।

आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया लोकनायक को इतना सस्ता न बना दें कि हर कुरसी छोड़नेवाला उनके समकक्ष हो जाये। जे०पी० से वी०पी० की तुलना मात्र जे०पी० का नहीं उनके तमाम प्रशंसकों का क्रूर परिहास व अपमान है। —अरुण कुमार (कंजा), गया

चिट्ठियां

मात्र यही विकल्प राजीवजी के पास है जो उनकी स्थिति को पुनः मजबूत कर सकता है? —जयकुमार कालानी, दर्शन पुरवा, कानपुर

सब हरि-जन हैं

'माया' (१५ अगस्त) में श्रीनाथद्वारा में हरिजन प्रवेश प्रकरण के संबध में वहां के स्थानीय विधायक सी०पी० जोशी का साक्षात्कार पढ़ा। पढ़कर दुख हुआ कि आजादी के चालीस साल बाद भी हरिजन छुआछूत अपमान और परतंत्रता की बेड़ियों में बंधे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि श्रीनाथजी के मंदिर में हरिजन दर्शन कर सकते हैं बशर्ते वे मंदिर के नियमों का पालन करें। हरिजन इसके लिए सहर्ष तैयार थे। इसके बाद भी क्यों प्रवेश नहीं करने दिया गया? रायपुर के सांसद को दर्शन करने के बाद हरिजन समझ कर उन पर हमला क्यों किया गया था? इससे श्री जोशी का कथन गलत साबित होता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कि श्रीनाथजी की संचालन समिति में फलां-फलां पदों पर अनुसूचित जाति और आदिवासी नियुक्त हैं, पर उन नामों में भंगी शब्द का कहीं भी नाम नहीं आया। अर्थात श्री जोशी को मालूम नहीं कि हरिजनों में कई जातियां शामिल हैं। यह प्रवेश समस्त हरिजनों का नहीं था, बल्कि हरिजनों के भंगी समुदाय का प्रवेश था। अतः श्री जोशी जगजीवन राम व पहाड़िया दंपती का उदाहरण देकर बात को रफा-दफा करना चाहते हैं। अब यह सोचना गलत नहीं होगा कि कहीं अपमानित भंगी समाज भी उबल न पड़े। —राधेश्याम चांवरिया, घनश्याम चांवरिया, माण्डलगढ़, जि० भीलवाड़ा (राज०)

सीढ़ी का भेद

'माया' १५ अगस्त का अंक पढ़ा। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का यह कथन शत प्रतिशत सही है कि बोफोर्स प्रकरण उलझने से पूर्व ही अमिताभ बच्चन को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे उनकी दोस्ती बनी रहती और पार्टी पर नया धब्बा नहीं लगता। तारिक अनवर कुछ ज्यादा बोल गये हैं। अपने साक्षात्कार में कहते हैं कि अमिताभ बच्चन पर लगे आरोपों का सरकार से क्या लेना-देना। जबकि 'इंडियन एक्सप्रेस' में स्विट्जरलैंड में खरीदे मकान का दस्तावेज छप चुका था। दूसरी तरफ बच्चन बंधु कह चुके हैं कि सभी कार्य राजीव की जानकारी में हुए हैं। अनवर साहब कहते हैं—वी०पी० सिंह वही सीढ़ियां चढ़े हैं जो हर कांग्रेसी चढ़ते हैं, समय बतायेगा वह कितने ईमानदार हैं। तब तारिक साहब कौन सी सीढ़ी चढ़ कर ऊपर पहुंचे हैं? —त्रिभुवन प्रसाद सिंह, "त्रिपुरारी" छतहार-भागलपुर (बिहार)

राष्ट्रीय मसले छूट गये

अगस्त, '८७ के अंक में रंजना कक्कड़ द्वारा राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमण से साक्षात्कार में पूछे गये अधिकांश प्रश्न राष्ट्रपति के पद से संबंधित संवैधानिक प्रश्न ही थे। साक्षात्कार में यदि महत्वपूर्ण व अतिचर्चित राष्ट्रीय मसलों पर (विशेष रूप से उन मसलों पर राष्ट्रपति का क्या दृष्टिकोण रहेगा जिन पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच मतभेद की स्थिति पैदा होने की काफी संभावना है) कुछ जानकारी प्राप्त की जाती, तो साक्षात्कार अधिक प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण बन सकता था। —अशोक कुमार शर्मा, ग्राम गुढ़ा आशिकपुरा, पो० बिवाई, जयपुर (राज०)

खंडन

'माया' के ३१ जुलाई, १९८७ के अंक में प्रकाशित कथा 'युवा इंका में उठापटक' में मेरे संबंध में प्रकाशित किया गया है कि मुजफ्फरनगर में कागज के व्यापारी मोहम्मद इरफान ने शहर युवा इंका का अध्यक्ष पद व्यापारिक लाभ उठाने के लिए हथियाया था। इसके एवज में उसने एक मारुति वैन दी थी। यह सरासर गलत व बेबुनियाद है। मैं आरम्भ से ही कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता रहा और २० सूत्री कार्यक्रमों और पार्टी के अन्य कार्यों में अग्रणी रहा हूं। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर प्रदेश युवा कांग्रेस-इ अध्यक्ष सांसद श्री संतोष सिंह ने युवक कांग्रेस-इ अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे दिया है। —मोहम्मद इरफान, अध्यक्ष शहर युवा इंका मुजफ्फर नगर

खयालात

० मैं खुद को काफी सुरक्षित महसूस करता हूं। **—बी०बी०सी० को दिये राजीव गांधी के एक साक्षात्कार से**

यदि सेंध लगे मकान का चौकीदार यह कहे कि उसने चोरी नहीं की है तो, क्या उस चौकीदार को फिर भी उस पद पर बने रहने की आज्ञा दी जानी चाहिए? **—वी०पी० सिंह**

० विपक्षी एकता कोई कल्पवृक्ष नहीं है, जिसमे सारी परेशानियां हल हो सकें। **—जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर**

जब तक परमात्मा ने मुझे जिंदा रखना है, कोई भी मुझ पर हमला नहीं कर सकता। **दिनमान को दिये ज्ञानी जैल सिंह के एक साक्षात्कार से**

० अखबार वाले हमारी पूरी बात नहीं छापते जबकि 'रजवा' (विश्वनाथ प्रताप सिंह) के लिए अखबार रंग देते हैं।...हमारा प्रधानमंत्री बहुत सीधा है और नोबल आदमी है, लेकिन वही कहावत है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटें सो रजवा के कुत्ते उनका मुंह चाट रहे हैं। **राज्यसभा सदस्य कल्पनाथराय**

० संसार के इस हिस्से (दक्षिण एशिया) का भारतवर्ष को संरक्षक होना चाहिए। **—लंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने**

० आप लोगों (सांसदों) के रोजाना के शोरगुल से मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। **—बलराम जाखड़, लोकसभाध्यक्ष**

० पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब सरकार की कांग्रेस पार्टी है। **—अमेठी के पूर्व राजा रणंजय सिंह**

० महात्मा गांधी ने कहा था—डरो मत और डर निकल गया दिल से, लेकिन आज तो डर-ही-डर है। जान का डर, चोरी का डर, सभी तरह के डर—आजाद मुल्क में यह अच्छी बात नहीं है। **—बी०बी०सी० को दिये विजय लक्ष्मी पंडित के एक साक्षात्कार से**

ज्ञानी जैल सिंह

जयवर्द्धने

डिंपल कपाड़िया

० मैं सोचती हूं कि राजेश ने मुझसे शादी करने का अचानक फैसला अंजू महेंद्रू से अपने संबंधों के कारण लिया था। मुझे पता नहीं इससे वह अंजू से बदला लेना चाहता था या अपने टूटे हुए दिल को जोड़ना। **—'इलस्ट्रेटेड वीकली' में डिंपल कपाड़िया**

० मेरे पिता ने कहा था कि नंबर एक खिलाड़ी बनना असंभव है। मैं भी यह गौरव पाने के बारे में नहीं सोचती थी। मैं काफी आश्चर्यचकित हूं। **—विश्व में महिला टेनिस की नंबर एक खिलाड़ी बनने के बाद स्टेफी ग्राफ**

० मैं उसका पति बनूंगा, कोई निजी सहायक नहीं। बेनज़ीर अपने राजनीतिक और पार्टी मामलों में स्वतंत्र होंगी। **—बेनज़ीर भुट्टो के मंगेतर आसिफ अली जरदारी**

सूखा-उत्सव

मुल्क के सूखे को धोबीपाट मारकर दिल्ली दरबार उसके सीने पर चढ़ा उसका थोबड़ा बिगाड़े दे रहा था। कुछ ही देर पहले देश के योजना आयोग ने सूखे से हाथापाई कर पाने में अपनी बेबसी दिखा दी थी। आयोग का कहना था कि हमारी सारी कमाई मुल्क का 'मारुति कल्चर' निगल गया। अब हमारी दशा 'सूखे के कंकाल' जैसी ही है। इस पर दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गया था— "इतनी मिन्नत के बाद अपनी धूल चाटती 'इमेज' को निखारने के लिए एक वरदान के रूप में सूखा मिला। ये लोग कहते हैं कि सूखे से भिड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं है। मैं अकेले ही इस साले सूखे की ऐसी-तैसी कर दूंगा।" दिल्ली दरबार ने एक और मुक्का सूखे के चेहरे पर जड़ा, तो वह 'नर कंकाल' के रूप में उभर आया। पीछे से नये दरबारी तथा दून स्कूली सखा सुमन दुबे ने दिल्ली दरबार के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रख दिया— "यार, तुम तो पसीना-पसीना हो रहे हो। मैं मीडिया का आदमी हूं। मुझे मालूम है कि किस तरह चीजों को प्रजेन्ट किया जाता है। मैं तुम्हें सूखा-हीरो प्रोजेक्ट कर दूंगा। इतनी कसरत की जरूरत नहीं है। उठो ससुराल से इटेलियन बियर की नयी क्रेट आयी है।"

सुमन दुबे दिल्ली दरबार को सूखे की मंत्रिमंडलीय पालकी पर बिठा कर अंदर ले गये। वहां रोमी चोपड़ा अपने एक दर्जन विज्ञापन आर्टिस्टों के साथ मौजूद थे। उन्होंने 'मारुति कल्चर' के लहजे में 'हलो' की, और उसके बाद बोलना शुरू कर दिया— "मैं तो मास्को में भारत उत्सव की बल्लियां खुलवा रहा था। उसी समय मुझे आपका एस०ओ०एस० मिला कि दिल्ली दरबार भारत में सूखा उत्सव मनाने का फैसला ले चुका है। यह बहुत अच्छा निर्णय है। भारत में इस बार ऐसा उम्दा सूखा उत्सव आयोजित करूंगा कि लोग झूम उठेंगे। पेरिस, लंदन, अमरीका और मास्को के भारत उत्सव पीछे रह जायेंगे।" दिल्ली दरबार ने रोमी चोपड़ा के मुक्का मारकर पीठ थपथपा दी। चल फटाफट सूखा उत्सव का 'ब्लू प्रिंट' बना ले। "अब ज्यादा समय नहीं रह गया है।" रोमी चोपड़ा ने अपने लंबे कुरते के नीचे से ब्लू प्रिंट का एक पुलिंदा निकाला और उसमें से एक निकाल कर दिल्ली दरबार के सामने पेश कर दिया। दिल्ली दरबार ने खुशी-खुशी हाथ में लेते हुए देखा और सुमन दुबे की तरफ मुखातिब होकर कहा, "रोमी का तो मैं इसलिए लोहा मानता हूं। फरमायसी प्रोग्राम में इसका जवाब नहीं है। ...लेकिन यह क्या! इसमें तो सूखे के साथ बाढ़ का भी ब्लू प्रिंट है। मुझे तो केवल सूखा चाहिए।" रोमी ने आगे बढ़कर ब्लू प्रिंट का पन्ना पलट दिया— "यह टू इन वन है। अगर आप चाहें, तो सूखा और बाढ़ दोनों उत्सव एक साथ आयोजित कर सकते हैं। वह जो आपने कंप्यूटर स्मगल करा दिया था, उसका यह कमाल है। देखिए, देखिए तीन-दो-पांच पन्ने पर बोफोर्स दलाली 'मायनस' सूखा बराबर दरबार! आप जैसे ही बोफोर्स की दलाली में से सूखे को घटायेंगे, तो पूरे देश में सिर्फ दिल्ली दरबार की जयजयकार ही रह जायेगी। इसीलिए यह ३-२-५ पन्ना बहुत महत्वपूर्ण है।" दिल्ली दरबार खुशी से उछल पड़ा— "रोमी तेरा मुंह चूम लेने को दिल करता है। लेकिन तेरी यह दाढ़ी मुझे ऐसा करने से रोक रही है। तूने तो मेरे दिल को बाग-बाग कर दिया। तेरा कमीशन साढ़े सात की जगह पूरे १५ प्रतिशत। क्या गणित फिट की है। सारे मुल्क में एलान करा दो कि हम बहुत जोश-खरोश के साथ 'सूखा उत्सव' मनाने जा रहे हैं। सारे सूखा पीड़ित इलाकों में बड़े-बड़े कलर पोस्टर लगाओ कि मुल्क में सूखा उत्सव आयोजित हो रहा है। गांव-गांव में वीडियो फिल्में बनाकर दिखाओ कि हर तरफ पानी-ही-पानी है। अनाज के सारे गोदाम खोल दिये गये हैं। हर आदमी मनों अनाज अपनी कारों पर लादकर लिये जा रहा है। हर किसान को सरकारी कर्मचारी घरों पर जाकर जबरदस्ती राहत और तकावी दे रहे हैं। ऐसा माहौल पैदा कर दो कि लोग सूखे का नाम ही भूल जायें।" रोमी चोपड़ा ने ब्लू प्रिंट को अपने हाथ में लेते हुए कहा, "सर, आपने इस सूखा उत्सव की आत्मा को पूरी तरह पकड़ लिया है। इसी को कहते हैं—नेतृत्व। अरे वह राजा मांडा क्या खाकर इस मुल्क का नेतृत्व करेगा, जिसे हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखायी पड़ता है। अगर कहीं ईमानदारी बची है, तो मात्र 'भ्रष्टाचार' में। सर, इस सूखा उत्सव के लिए एडवांस उस बोफोर्स कमीशन से ले लें या फिर..."

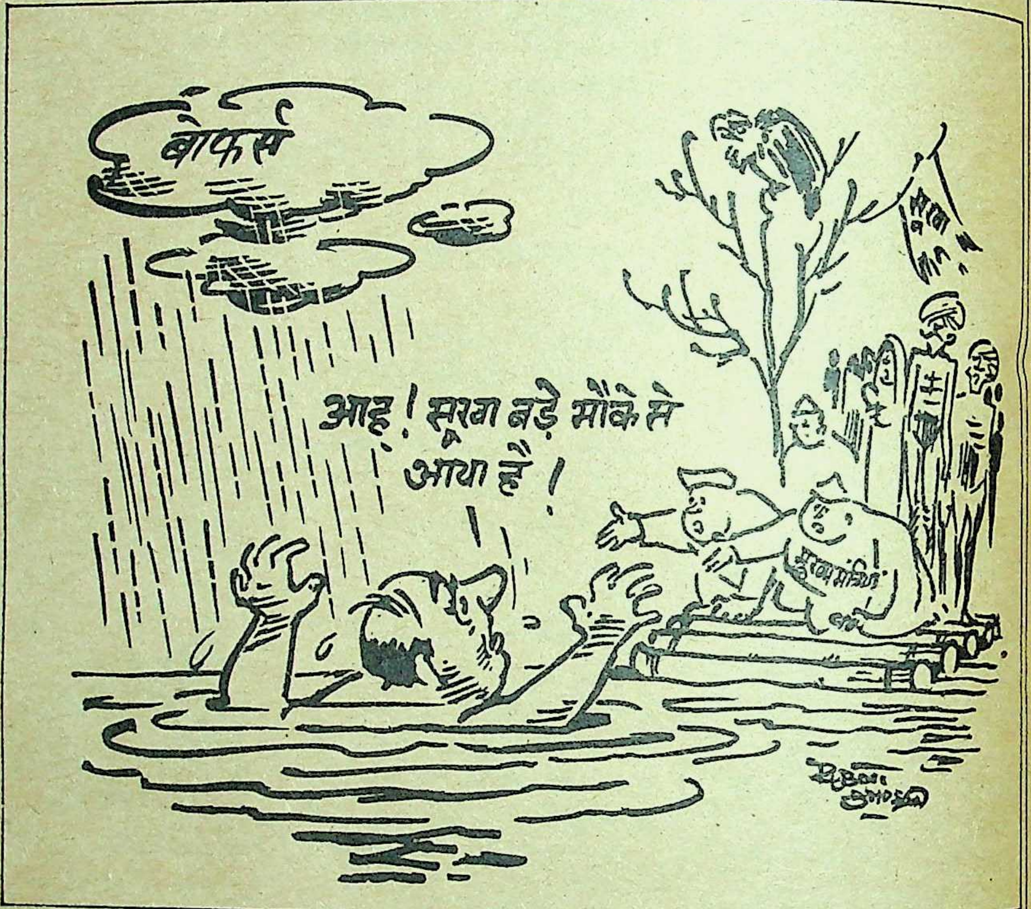
बोफर्स
आह! सूखा बड़े मौके से आया है!
सूखा

दिल्ली दरबार 'बोफोर्स कमीशन' की बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसके मुंह से गुस्से का धुंआ निकलने लगा, "रोमी, मैंने पिछले दिनों संसद में राग अहीर भैरव गाकर सुनाया था— "मैया मैं नहीं (बोफोर्स) माखन खायो," क्या तूने नहीं सुना! जब मैं कह रहा हूं कि मैंने मक्खन नहीं खाया, तो तुझे यकीन कर लेना चाहिए। "रोमी दिल्ली दरबार के चरणों में गिर पड़े, "सर, क्षमा कर दीजिए। आदत से मजबूर हूं। चोर चोरी से जा सकता है, लेकिन हेरा-फेरी उसका दामन पकड़े रहती है। आइंदा बोफोर्स के कमीशन का नाम जबान पर आये, तो उसे कटवा कर चील-कव्वों के हवाले कर दीजिएगा।" दिल्ली दरबार ने पसीज कर रोमी को चरणों से उठा लिया— "देख रोमी, सूखा हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अगर सूखा उत्सव मनाने के लिए हम लोग दलाली का पैसा खर्च करेंगे, तो इससे हमारे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए हम इस राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्र के धन से ही

मनायेंगे। हमने अपने अर्थशास्त्री मनटेक सिंह अहलूवालिया को कह दिया कि एक हजार करोड़ का फिलहाल प्रबंध राष्ट्र को निचोड़ कर करो। वह न्यू दिल्ली, तिवारी (एन०डी० तिवारी) से मिलकर धन की व्यवस्था कर रहे हैं। तुम मनटेक से एडवांस की बात कर लो।" रोमी ने आगे बढ़कर दिल्ली दरबार का हाथ चूम लिया— "सर, आपके हाथ में बहुत बरकत है।" रोमी जैसे ही पीछे हटे, सतीश शर्मा ने एक बाल्टी डिटोल से दिल्ली दरबार का रोमी द्वारा चूमा गया हाथ धो डाला।

> "तुम लोगों ने क्या तीर मारा है। सूखा तो मैंने पैदा किया है। मैंने तो बादलों पर धारा १४४ लगा दी है। अगर बादलों ने हमारे प्रदेश में घुसने की कोशिश की, तो मेरी पी०ए०सी० उसकी कमर ही तोड़कर रख देगी। 'सूखाश्री' तो मुझे ही मिलना चाहिए"

हाथ धोने का काम चल ही रहा था कि पं० कमलापति त्रिपाठी अपने लल्लू (लोकपति त्रिपाठी) को उंगली पकड़ाये हुए दिल्ली दरबार में आ धमके। लल्लू अपना अंगूठा चूस रहे थे। पंडितजी के दस कदम पीछे बहूजी (चंद्रा त्रिपाठी) बनारसी साड़ी में गुड़िया बनी खड़ी थीं, पंडितजी ने लल्लू के पहले एक चपत लगायी— "साठ का हो गया, लेकिन अंगूठा चूसने की आदत नहीं गयी। चल दिल्ली दरबार को प्रणाम कर।" लल्लू ने प्रणाम करके फिर से अपने मुंह में अंगूठा घुसेड़ लिया और धीरे से कहा, "तूही तो कहा रहे कि दिल्ली दरबार मा तू अगर लल्लू बना रहे, तो तुहार मुख्यमंत्री बाला काम बन जाई। यही लिये तो हम अंगूठा चूसत हैं।" पंडितजी ने लल्लू को अनसुना करते हुए दिल्ली दरबार की घेराबंदी शुरू कर दी, "हमारी तो बड़ी मुश्किल है। लल्लू दिन रात रोता रहता है कि हमका यू०पी० के मुख्यमंत्री बाली कुरसी खरीद दो और दूसरी ओर वी०सी० शुक्ला, रामधन, आरिफ और वह अपना विश्वनाथ पीछे पड़े हैं कि बाबू हमार साथ आओ। यहां इज्जत है। हम नहीं समझ पा रहे कि का करें। एक तरफ खाई दूसर ओर कुआं। और अब यह इनदर देवता और आफत कर दिहिन हैं। सूखा तो प्राण लिये ले रहा है। सुना है आप उत्सव मनाये की सोच रहे हैं।" सूखा का नाम सुनते ही दिल्ली दरबार प्रफुल्लित हो उठे— "आपने ठीक सुना है पंडितजी! हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सूखा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की योजना बना रहे हैं। आप को भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिलेगा। हम पार्टी स्तर पर भी एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको भी रखेंगे।" दिल्ली दरबार ने पसीना पोंछते हुए पंडितजी से पूछा, "अर्जुन सिंह तो कह रहे थे कि सूखा वरदान के रूप में आया है। बोफोर्स आदि इत्यादि इसके नीचे दब जायेंगे। लेकिन आप तो उलटी बात कर रहे हैं।" पंडितजी ने अपने स्वर को तीखा करते हुए कहा, "भांग हमने खाई, नशा उस चुरहट लाटरी वाले को चढ़ा। अरे अर्जुन सिंह पूरी तरह डुबो देगा। सूखा खाने के लिए आता है, किसी को बचाने के लिए नहीं—और फिर यह सौ साला सूखा है। कहते हैं कि जिस देश का राजा पापी हो जाता है, उस देश में सूखा-अकाल पड़ता है। देखो भई, मैं तो मुंहफट हूं। जब तक किसी चीज में मेरा भला न हो तो मैं खरी ही बात कहता हूं। जब यह बिना मां का लल्लू गला फाड़ कर मुख्यमंत्री की कुरसी के लिए रोता है, तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। अगर आज इसकी मां जिंदा होती, तो मुझे जीने देती, इतनी जरा-सी चीज के लिए। मैं विद्रोही कांग्रेसियों के खिलाफ एक बयान जनपथ पर लिखकर, रख आया हूं। लेकिन मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए क्या यह शोभा देता है कि मैं किसी के खिलाफ बयान जारी करूं! मैं बयान जारी भी कर सकता हूं, अगर कोई मेरे लल्लू के आंसू पोंछ दे।" दिल्ली दरबार ने लल्लू की तरफ चाकलेट फेंकते हुए पंडितजी से कहा, "इस समय तो कुरसी खाली नहीं है। लेकिन जब खाली होगी, तो विचार किया भी जा सकता है। पंडितजी आप घबरायें नहीं। सौ साल में तो घूरे के दिन भी बदलते हैं। और आप तो पंडित हैं। आप वह बयान जारी कर दें मैं आपको सूखा उत्सव की पार्टी कमेटी का संयोजक बनाने की बात भी सोच रहा हूं। वैसे तो उसका मुख्य काम चंदा उगाहना होगा। दिखावे के लिए उसमें कुछ और काम आप जोड़ सकते हैं।" दिल्ली दरबार में धड़ाम की आवाज के साथ एक बोरा आ गिरा। उसमें से धीरे से मध्य प्रदेशीय मोती लाल बोरा अवतरित हो गये। टिनोपाली बोराजी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया— "सूखानरेश की जय हो। मैंने सूखे के नाम पर अपने प्रदेश में हर तरफ हाहाकार मचवा दिया। आप अगर नहीं चल सकते हैं, तो एक-दो दिन के लिए अपनी कोई टीम सूखा पिकनिक के लिए भेज दें, ताकि वह यह अंदाज़ लगा सके कि मैं कितना प्रभावी हूं।" इसी बीच पहले से खड़े गुजराती अमर सिंह चौधरी ने आगे बढ़कर बोरा को ढंक लिया— "म०प्र० में क्या सूखा है। हुजूर सूखा देखने का मजा तो मेरे गुजरात में है। क्या झमाझम सूखा है कि देखकर तबीयत बाग-बाग हो जाये। पिछले दिनों आपकी जो टीम गयी थी, वह तो झूम उठी। मैं पिछले तीन साल से यज्ञ-मंत्र कराके अपने यहां इंद्र देवता के प्रवेश को रोके हुए हूं। मेरे गुजरात को तो 'सूखाश्री' की मानद उपाधि मिलनी चाहिए।" परदे के पीछे किसी युवक की किलकारी जैसा अमर सिंह चौधरी का 'सूखाश्री' का शब्द जानकी बाबू के कान में टकराया तो वह तुरंत बेपरदा हो गये, "यह क्या सरकार, कालाहांडी में सैकड़ों को ठिकाने लगा देने के बावजूद 'सूखाश्री' उड़ीसा को नहीं मिलेगा! सूखे पर तो हमारी अर्थ व्यवस्था टिकी हुई है।"

जानकी बल्लभ पटनायक दिल्ली दरबार के चरणों में बिछने ही जा रहे थे कि वीर बहादुर सिंह आधे दर्जन बुलेटप्रूफ जैकिट लादे घुस आयें। उन्होंने जानकी बाबू को पीछे धकियाते हुए कहा, "तुम लोगों ने क्या तीर मारा है। सूखा तो मैंने पैदा किया है। मैंने तो बादलों पर धारा १४४ लगा दी है। अगर बादलों ने हमारे प्रदेश में घुसने की कोशिश की, तो मेरी पी०ए०सी० उसकी कमर ही तोड़कर रख देगी। 'सूखाश्री' तो मुझे ही मिलना चाहिए। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तो राजा मांडा से पूछ लो कि मैंने बादलों पर धारा १४४ लगा रखी है या नहीं।" इतने में ही दिल्ली दरबार के बाहर शोर होने लगा। सारे लोग मुड़कर बाहर देखने लगें। जार्ज, सतीश और सुमन तेजी के साथ बाहर की ओर लपके। दिल्ली दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद एक-एक करके तीनों लौटे। दिल्ली दरबार ने इशारे से पूछा, "क्या हुआ। बाहर इतना शोरगुल क्यों हो रहा था!"

सुमन दुबे ने बाहर से लाये एक कागज को पढ़ते हुए कहा, "कुछ नहीं। गैरब्राह्मण इंकाई सांसद थे। शोर कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति भी एक ब्राह्मण को बना दिया गया। एक ज्ञापन देकर गये हैं।" दिल्ली दरबार ने जिज्ञासा प्रदर्शित करते हुए प्रश्न किया, "हमने किस ब्राह्मण को उपराष्ट्रपति बना दिया! हमने तो शंकर दयाल शर्मा को बनाया था। वह हो ब्राह्मण नहीं डाक्टर हैं।" सुमन दुबे ने करीब आकर बताया, "शंकर दयाल शर्मा डाक्टर के अलावा ब्राह्मण भी हैं।" दिल्ली दरबार सोच में डूबते हुए बोले, "अच्छा। तो यह शर्मा ब्राह्मण भी होते हैं। लेकिन वह ए०पी० शर्मा तो...।" सुमन ने अदब से कहा, "जी हां, वह ए०पी० शर्मा ब्राह्मण नहीं है। लेकिन शंकर दयाल शर्मा पूरे कान्यकुब्जी ब्राह्मण हैं। इन इंकाई सांसदों का यह भी कहना है कि अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ब्राह्मण हो गये हैं।" दिल्ली दरबार ने जोर का अट्टहास लगाते हुए कहा, "ये सांसद बहुत मूर्ख हैं। अरे भाई, राष्ट्रपति वेंकटरमण ब्राह्मण नहीं हैं, वह तो मद्रासी हैं। किसने कहा कि वह ब्राह्मण हैं!" सुमन दुबे खिसियाई हंसी हंसते हुए दिल्ली दरबार के कान में फुसफुसाये, "अरे यार, वह वेंकटरमण भी ब्राह्मण हैं। तुम फौरन विषय बदल दो। नहीं तो काफी किरकिरी होगी।" दिल्ली दरबार ने फौरन अपने तेवर बदल दिये, "इस समय हम सूखा उत्सव की बात कर रहे हैं। कोई और बात नहीं सुनना चाहते। हां तो आप लोग सूखे की बात को आगे जारी रखें।"

इसके बाद दिल्ली दरबार में गिटार पर राग सूखा शुरू हो गया और दरबारी झूम-झूम कर नाचने लगे।

—दरबारी लाल

छाया : सुनील सक्सेना

खाना हो, तो खाओ

जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जन्माष्टमी के दिन अपने दिल्ली स्थित आवास पर दोपहर के भोज पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया। चंद्रशेखर ने सामिष तथा निरामिष दोनों तरह का भोजन तैयार करने के लिए कहा। लेकिन जब यह बात श्रीमती चंद्रशेखर के कान में पहुंची कि कृष्ण जन्म के दिन घर में मांसाहारी भोजन बन रहा है, तो वह बिगड़ गयीं—"पत्रकारों को अगर शाकाहारी भोजन करना हो तो करें, नहीं तो अपने घर बैठें।"

चंद्रशेखर अपनी पत्नी या परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेने देते हैं। वह सुबह अगर घर पर होते हैं, तो अपने परिवार के साथ मात्र चाय पीते हैं। उसके बाद परिवार से उनका कोई संबंध दिन भर नहीं रहता है। चंद्रशेखर के स्टाफ ने उनको यह नहीं बताया कि श्रीमती चंद्रशेखर को कृष्ण जन्म के दिन मांसाहारी भोजन घर में बनाये जाने पर आपत्ति है। स्टाफ ने सोचा कि वे बाहर से मांसाहारी भोजन ले आयेंगे। इसके लिए किसी को कह भी दिया गया लेकिन जब श्रीमती शेखर को पता चला कि पत्रकारों के लिए बाहर से मांसाहारी भोजन मंगाया जा रहा है, तो वह फिर से बिगड़ीं, "अरे क्या पत्रकारों के लिए हम भगवान कृष्ण को भूल जायें। अगर घर में मांसाहारी भोजन आया, तो उसे हम सबके सामने बाहर फिकवा देंगे।" स्टाफ परेशान हो उठा, क्योंकि उसने चंद्रशेखरजी को बोल रखा था कि मांसाहारी भोजन भी है।

जब पत्रकारों को भोजन खिलाया जा रहा था, तो चंद्रशेखर को बताया गया कि कृष्ण जन्माष्टमी के कारण मांसाहारी भोजन नहीं बनाया गया, लेकिन श्रीमती चंद्रशेखर ने अपने एक खास आदमी को बाहर यह देखने के लिए भेजा कि यह देखकर आओ कि कहीं पत्रकार मांसाहारी भोजन तो नहीं कर रहे हैं। जब उस आदमी ने अंदर जाकर यह बता दिया कि पत्रकारों को मात्र शाकाहारी भोजन ही दिया गया है, तो कहीं जाकर पत्रकारों का खाना खराब होने से बचा।

शिवचंद्र की पाती

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डा० शिवचंद्र झा ने इंका आलाकमान को एक विस्फोटक गोपनीय पत्र दिया है। मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के विरुद्ध इस पत्र में कहते हैं कि कई संगीन आरोप लगाये हैं। मुख्य मुद्दा है कर्पूरी ठाकुर को विरोधी दल के नेता पद से अपदस्थ किये जाने पर दुबे का रवैया। राजनीतिक भेदिये सुराग खोलते हैं कि शिवचंद्र झा ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने तो कर्पूरी को अपदस्थ कर विपक्ष को ढहाने की कोशिश की है, लेकिन दुबे खुलेआम कर्पूरी की विरोधी दल नेता पद पर वापसी के लिए बेचैन हैं। शिवचंद्र झा ने कर्पूरी को इस तर्क के साथ विपक्षी नेता के पद से हटा दिया कि लोकदल के सभी ४६ विधायक दमकिपा के नाम से चुनाव जीते थे। इनमें से मात्र उन्नीस विधायकों ने विधानसभा को विधिवत लिखित सूचना दी है कि उन्हें अब लोकदल के विधायक के रूप में गिना जाये। इस लिहाज से शिवचंद्र झा का यह तर्क था कि कर्पूरी के साथ कानूनन महज १९ विधायक हैं। जब तक वह कम-से-कम ३३ विधायकों को लोकदल का सदस्य साबित नहीं करते, तब तक वह दुबारा विरोधी दल के नेता नहीं हो सकते। नाराज कर्पूरी ठाकुर ने शिवचंद्र झा के चुनाव क्षेत्र भागलपुर में 'धर्मयुद्ध' की मुनादी कर दी है। शिवचंद्र झा के हितैषी कहते हैं कि हाल के विधानसभाई सत्र में मुख्यमंत्री के इशारे पर कर्पूरी ठाकुर शिवचंद्र झा की बुरी तरह खिंचाई करते रहे हैं। इधर शिवचंद्र झा विरोधी मुहिम में दुबे चुपचाप पुरजोर मदद कर रहे हैं। आखिर दुबे-शिवचंद्र की भीतर-भीतर क्यों ठनी है? राजनीति के लाल बुझक्कड़ रहस्योद्घाटन करते हैं कि शिवचंद्र झा मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो ठहरे! बहरहाल, राजनीतिक पंडित पलकें बिछाये बैठे हैं कि आला कमान को लिखे गये शिवचंद झा के पत्र का फलाफल क्या निकलता है?

छाया : सुधांशु

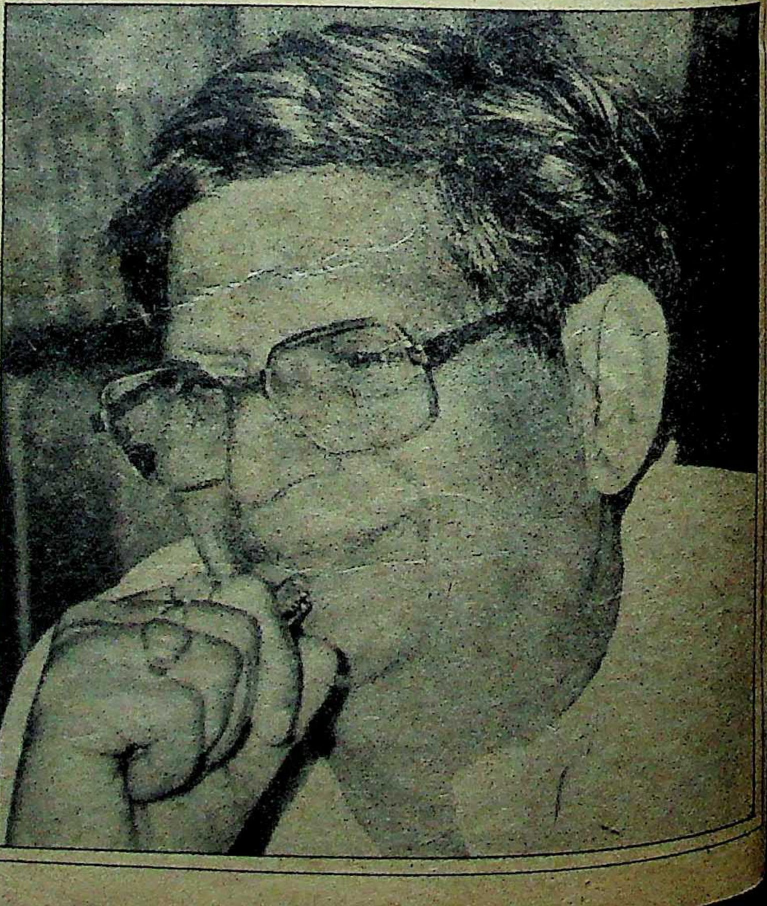

के नाम
मात्र
सभा को
है कि
यक के
हाज से
कि
न
वह कम-
किदल
ी, तब तक
ोता
री ठाकुर
भागल-
कर दी
कहते हैं
त्र में
ी
तरह
शिवचंद्र
चुपचाप
ाखिर
र क्यों
बुझ-
कि
दावे-
ाज-
बैठे
गये
फल

छाया : सुधांशु

जिनके लिये जागृत है
जीवन का हर क्षण.

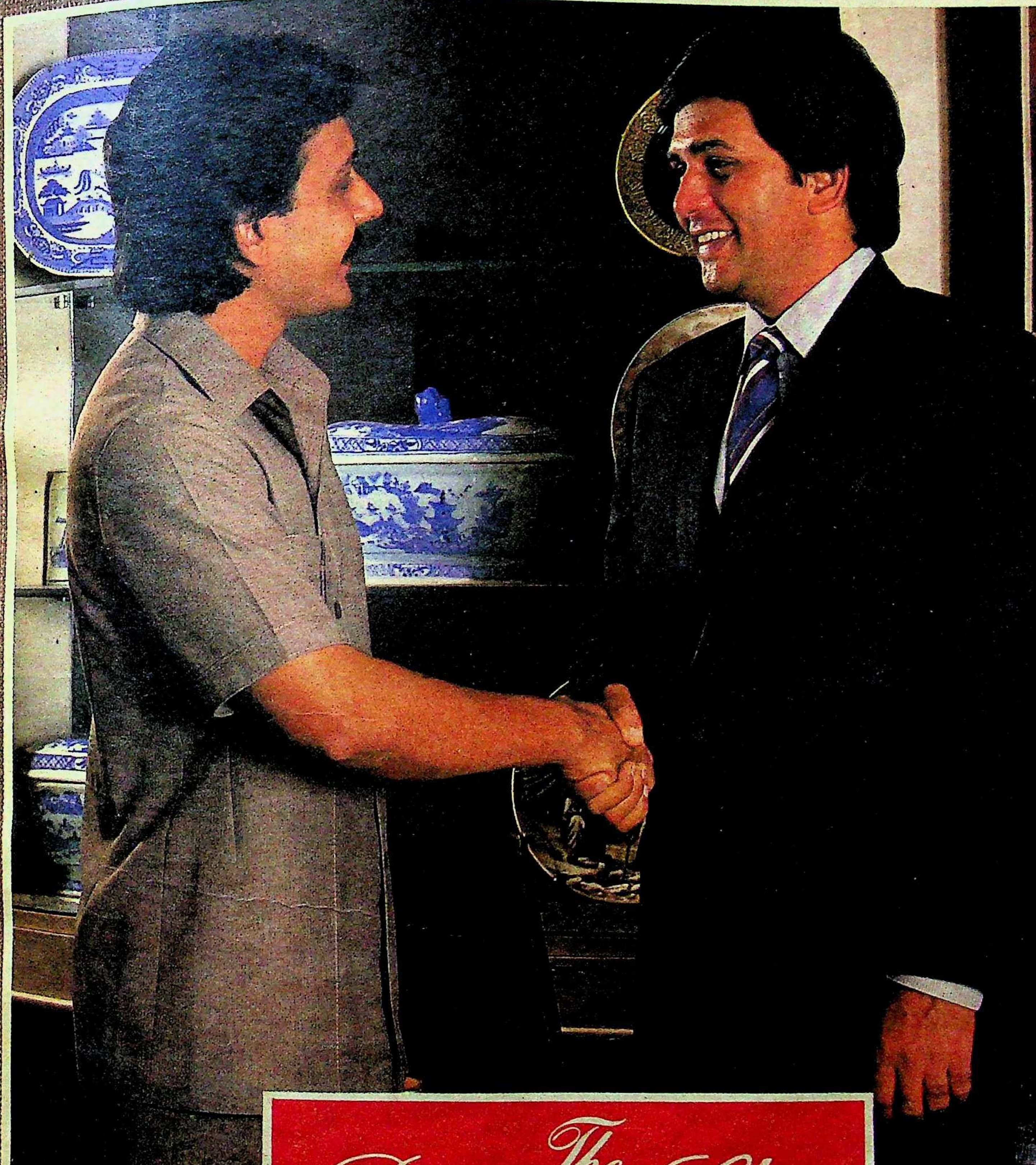

The Business Class
COLLECTION

उत्कृष्ट पॉलिएस्टर ब्लैंडेड सूटिंग्स.

एस.कुमार्स®

"निरंजन" ९९ मरीन ड्राइव, बम्बई-४०० ००२.
यहाँ प्रस्तुत है द बिज़नेस क्लास कलेक्शन से 'निरंजन' (बायें) और 'डेविस कप' (दायें)

मंज़िल हो मुश्किल, अनजान राहें
हीरो के साथ सब दूरियाँ मिट जाएँ

हीरो सुपरफास्ट (जैन्ट्स)

हीरो वी आई पी ५२.५ सै.मी. (लेडी)

हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना

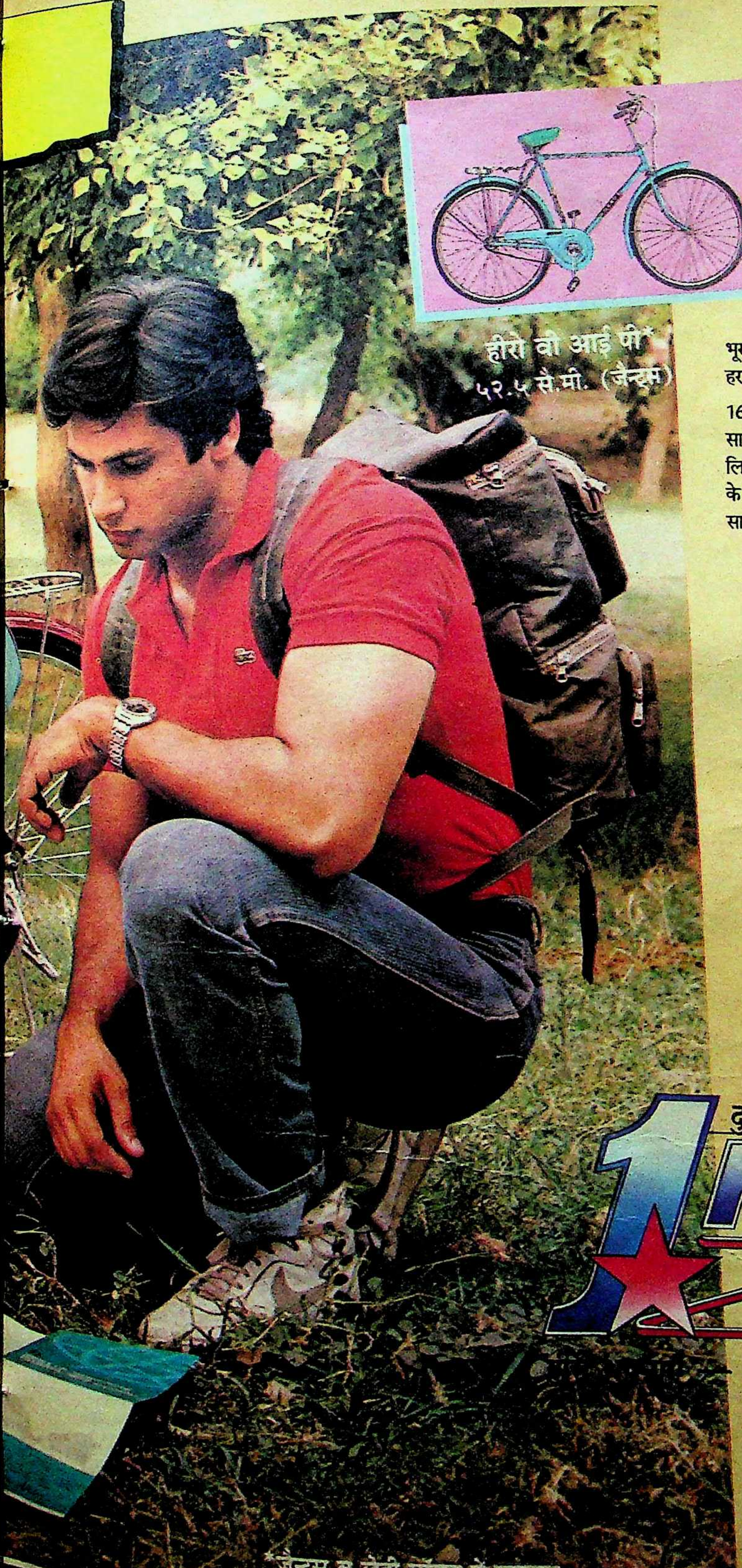
हीरो वी आई पी*
५२.५ सै.मी. (जैन्ट्स)

*जैन्ट्स व लेडी मॉडल में उपलब्ध

हीरो हाई-स्पीड (जैन्ट्स)
३ स्पीड फ्रीव्हील

कहीं पहुँचने की जल्दी या शहर से बाहर तफरीह का मूड, जब हीरो साथ है तो रास्तों के पत्थरों की भला किसे परवाह!

भूरा, हरा, लाल, सिन्दूरी। चाहे काला या नीला। हीरो हर रंग में जमे।

16 मॉडल जिनमें पाँच बच्चों के लिए हैं। गियर के साथ या बिना गियर। हर रंग, हर साइज़ में। सबके लिए। छोटी डगर हो या लम्बा सफर, हीरो की सवारी के क्या कहने। तभी तो है यह दुनिया की नं० 1 साइकिल।

हीरो यूनिबाइक ५२.५ सै.मी.

हीरो

मंज़िल मिलाए
दूरियाँ सिमटाए

दुनिया भर में नं० 1

HERO BICYCLES

नं० 1 होने का अनुभव पाएँ।

अब दुनिया की अधिकतम बिकने वाली साइकिल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स की ओर अग्रसर।

HC-NP-201

ताज़गी का
एक पल...
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESH
...एक पल
में ताज़गी
FUSION/RAJ/5
रजनीगन्धा पान मसाला
तुलसी ज़र्दा घराने की अनुपम भेंट

लेकिन प्रलय नदारद !

अंधविश्वास के सामने दर्शन-विज्ञान किसी की नहीं चलती। इस वैज्ञानिक युग में भी यूगोस्लाविया के एक शहर के पांच लाख नगरवासियों ने विश्वास कर लिया कि सैंट इलियास की स्मृति में मनाये जानेवाले ईसाई पर्व यानी २ अगस्त को भोर में एक जलजले के रूप में कयामत आनेवाली है, जिसमें पहाड़ धसकने लगेंगे, धरती फटने लगेगी और उस दिन से ऐसा महाप्रलय शुरू होगा कि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। एक अफवाह की तरह प्रलय की भविष्यवाणी अचानक घर-घर नहीं पहुंची थी, बल्कि किसी ज्योतिषि का नाम लेकर सप्ताहों पूर्व से लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और बहुत सोच-समझकर विश्वासपूर्वक बड़ी बेचैनी से वे २ अगस्त की प्रतीक्षा में थे। दूसरी ओर, सरकारी प्रचारतंत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि से धुंआधार प्रचार किया जा रहा था कि यह सब बकवास है। दुनिया भर में लगे भूकंपन मापक केंद्रों की रिपोर्टों का हवाला देकर वैज्ञानिक दूरदर्शन पर बता रहे थे कि दो अगस्त की सुबह इस क्षेत्र में भूकंप की कोई संभावना नहीं है। जिन लोगों का नाम लेकर यह भविष्यवाणी किये जाने की चर्चाएं थीं, उन सबने दूरदर्शन पर आ-आकर लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है।

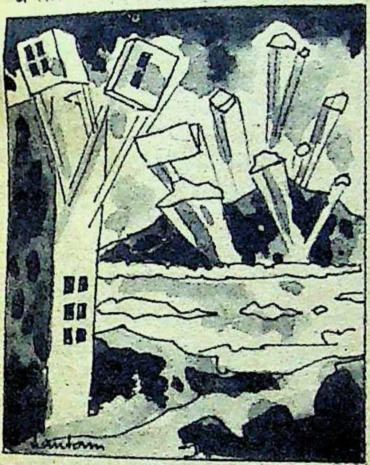

लेकिन एक अगस्त की शाम होते-होते पूरा शहर खाली हो गया। विज्ञान हार गया था और जीत अंधविश्वास की हुई। वे लोग भी उस दिन शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गये थे, जो इस भविष्यवाणी को बकवास बता रहे थे। शहर से दूर इन लोगों ने बड़ी बेचैनी से रात गुजारी और २ अगस्त की भोर में तो उनका भय चरम सीमा पर था। ये सब जलजले की प्रतीक्षा कर रहे थे, दिन निकल आया, लेकिन न प्रलय को आना था, न वह आयी। बड़ा मजेदार दृश्य था—सामूहिक रूप से मूर्ख बने नगरवासी अपने-अपने माल-असबाब के साथ शहर लौटने लगे और दोपहर तक शहर फिर से आबाद हो गया। एक ऐसे तूफान से लोग गुजरे थे—जो आया ही नहीं था—सब एक दूसरे को न आये इस प्रलय से बच जाने के लिए बधाइयां देना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपनी इस मूर्खता पर खुशियां मनायें या अपना माथा पीट लें।

विवाह का सुपर मार्केट

अखबारों के वैवाहिक विज्ञापनों के जरिये उपयुक्त वर-वधू की तलाश में काफी समय लग जाता है। अतः समय की बचत करने के लिए टोकियो में एक कंपनी की स्थापना हुई है। यह कंपनी उपयुक्त जोड़ी की तलाश करनेवाले स्त्री-पुरुषों को अपने जोड़ीदार का चयन करने का प्रत्यक्ष अवसर देती है और इसके लिए शुल्क भी वसूल करती है। एक बड़े कमरे में ऐसे स्त्री-पुरुष एकत्र होते हैं और प्रत्यक्ष बातचीत के जरिये अपने जोड़ीदार का चुनाव करते हैं। तीन मिनट के समय में ही दोनों को एक दूसरे की रुचि, शिक्षा, आय के साधन एवं घर-परिवार के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लेनी होती हैं। इस प्रकार एक पुरुष अनेक विवाह योग्य महिलाओं से और एक महिला अनेक विवाह योग्य पुरुषों से तीन-तीन मिनट के लिए मिलती है। जिससे जिसका मन मिल जाता है, वे विवाह-बंधन में बंध जाते हैं। यह कंपनी 'विवाह के सुपर मार्केट' के रूप में प्रसिद्ध होती जा रही है।

पिछले दिनों ऐसे ही एक आयोजन में ४६ पुरुषों और ३९ महिलाओं ने भाग लिया। ४ घंटे की बातचीत के बाद १३ जोड़ियों ने विवाह-बंधन में बंधने की घोषणा कर दी, शेष स्त्री-पुरुषों को उपयुक्त साथी नहीं मिला। अब वह ऐसे ही अगले आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उपयुक्त साथी की उनकी तलाश पूरी हो सके। बहरहाल, अभी यह देखना शेष है कि ऐसे सुपर मार्केट में 'माल' की तरह पसंद करके रचाये गये ये विवाह कितने दिनों तक टिकते हैं?

मक्खियों का विद्रोह

मियामी विश्वविद्यालय में मलेशिया से आया एक छात्र इन्न सियांग ओजी अफ्रीका की जहरीली मक्खियों पर शोध कर रहा था। इसी शोध के सिलसिले में वह कोस्टारिका के ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा था कि अचानक अफ्रीकी मक्खियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। एक-डेढ़ घंटे बाद उसके साथियों ने उसे मृत पाया। उसके शरीर पर इन मक्खियों ने आठ हजार डंक मारे थे। जिन मक्खियों की तलाश में वह निकला था, वे उसे मिलीं जरूर, लेकिन उनके बारे में जानकारी देने के लिए वह जीवित नहीं बचा।

ये अफ्रीकी मक्खियां इतनी जहरीली होती हैं कि जिसे वे डंक मार दें, उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। पूरा अमरीका महाद्वीप इन दिनों इन जहरीली मक्खियों से भयाक्रांत है। साओ पाओलो विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए १९५६ में अफ्रीका से कुछ मक्खियों को गुलाम बनाकर लाया गया था। लेकिन १९५७ में किसी दुर्घटनावश ये मक्खियां कैदखाने से भाग निकलीं और पिछले ३० वर्षों में इन्होंने अपनी संख्या इतनी बढ़ा ली है कि आज दक्षिणी और मध्य अमरीका के जंगलों में इनकी २० लाख बस्तियां बस चुकी हैं और संख्या करोड़ों में हो गयी है। इनकी यह विशालकाय फौज उत्तरी अमरीका को निगल जाने के लिए ३००-किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तरी अमरीका की ओर बढ़ रही है, और आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगले वर्ष के अंत तक जहरीली मक्खियों की यह फौज न्यूयार्क सहित अमरीका के अनेक प्रमुख नगरों पर हमला कर देगी। देखना है कि परमाणु हमले से बचाव की व्यवस्था में लगी अमरीका की सरकार अफ्रीकी मक्खियों के हमले का कैसे सामना करती है?

—संयोजन : विनोद मिश्र

साक्षात्कार/प्रणब मुखर्जी

मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी

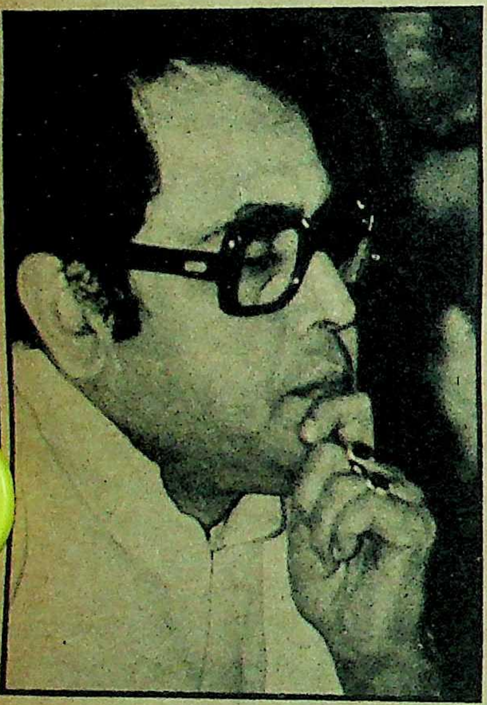

राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने ७ अगस्त शुक्रवार को कलकत्ता विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट हाल में आयोजित अपनी पार्टी की पश्चिम बंगाल शाखा की बैठक में पार्टी को तोड़ देने और कांग्रेस-इ में वापस जाने का स्पष्ट संकेत किया। यह बैठक बंद कमरे में हुई थी। उस गुप्त बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रणब बाबू ने कहा, "पहले एक बार कांग्रेस को तोड़कर बंगाल कांग्रेस बनायी गयी थी। उससे क्या लाभ हुआ? उस समय कांग्रेस टूटी थी, तभी तो सी०पी०आई (एम) आज पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ हो सकी।

उसी तरह अब विश्वनाथ प्रताप सिंह दक्षिणपंथी प्रतिक्रियाशील शक्तियों की सहायता से कांग्रेस को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी हालत में कांग्रेस को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। कांग्रेस कमजोर होगी, तो देश कमजोर होगा। कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है। फिर राजीव भी अब बहुत बदल चुके हैं। वह इंदिराजी के बताये मार्ग पर चलने लगे हैं। पार्टी के अंदर लोकतंत्र को प्रतिष्ठा मिली है। इंदिराजी के अनुयायियों को फिर महत्व दिया जा रहा है।"

राज्य के २०८ पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस-इ में वापसी की तैयारी शुरू हो गयी। इस बैठक में राज्य स्तर के सभी नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन राज्य शाखा के अध्यक्ष डा० शिशिर बसु को आमंत्रित नहीं किया गया था। डा० बसु इस समय असंतुष्ट नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनजागरण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कांग्रेस-इ में वापस जाने के खिलाफ हैं।

लेकिन १३ अगस्त, १९८६ को नेताजी इनडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रणब मुखर्जी ने साफ शब्दों में कहा था कि राजीव गांधी की हठधर्मी कार्यप्रणाली के विरुद्ध मेरा धर्मयुद्ध चलता रहेगा और किसी भी हालत में मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद गंगा में न जाने कितना पानी बह गया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस ने अनेक सीटों के लिए प्रत्याशी खड़े किये, लेकिन उस कांग्रेस को कुल एक लाख छियासी हजार वोट मिले। पार्टी की राज्य शाखा के अध्यक्ष डा० शिशिर बसु को मात्र सात सौ मत मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गयी थी। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की जब ऐसी स्थिति चल रही थी, तभी दिल्ली में पासा पलटा। असंतुष्ट नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने के बाद कांग्रेस-इ हाईकमान मुसीबत में फंस गयी, तो उसने जी०के० मुपनार के माध्यम से प्रणब मुखर्जी से संपर्क स्थापित किया। फिर प्रणब बाबू ने राजीव का समर्थन करना शुरू किया। प्रणब बाबू बड़े सफल प्रशासक और कुशाग्र बुद्धि के राजनीतिक नेता हैं। राजनीति में सूझ-बूझ और समझदारी से काम लेने के कारण भारत भर में उनकी प्रसिद्धि है। इसलिए संकट की इस घड़ी में उनकी कांग्रेस-इ में वापसी की संभावना ने भारत की राजनीति में एक नयी हलचल पैदा कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में 'माया' ने प्रणब बाबू से विस्तृत बातें की हैं। प्रस्तुत हैं, उसके मुख्य अंश:

माया: क्या आप कांग्रेस-इ में शामिल हो रहे हैं?

प्रणब: मैंने तो कांग्रेस-इ से इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए इस मामले में पहल करने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है।

माया: क्या इस संबंध में कांग्रेस-इ हाईकमान से कोई बात हुई है?

प्रणब: औपचारिक ढंग से तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अनौपचारिक ढंग से कुछ हुई है।

माया: आप पर जारी किये गये निष्कासन-आदेश को निरस्त कर आपको कांग्रेस-इ में वापस लिया जायेगा या आप अपनी गलती स्वीकार कर कांग्रेस-इ में लौट जायेंगे?

प्रणब: यह तो अटकल पर आधारित सवाल हुआ। पहले आधिकारिक तौर पर बातचीत तो शुरू हो।

माया: यानी आप किसी भी सूरत से कांग्रेस-इ में लौटने के लिए तैयार हैं?

प्रणब: यह सवाल भी बेतुका है। मैं तो शुरू से कांग्रेसी हूं। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी।

माया: लेकिन आपने तो कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से अलग पार्टी बनायी थी? कांग्रेस हाईकमान के विरुद्ध धर्मयुद्ध की घोषणा की थी?

प्रणब: लेकिन कांग्रेस कलचर (संस्कृति) के बाहर होकर नहीं। फिर मेरा धर्मयुद्ध तो अब भी चल रहा है। हठधर्म के विरुद्ध मेरा क्रूसेड (धर्मयुद्ध) था। कांग्रेस को इंदिराजी के बताये मार्ग से हटाये जाने के विरुद्ध मेरा संघर्ष था।

माया: अब क्या कांग्रेस-इ के अंदर परिस्थितियां बदल गयी हैं?

प्रणब: इंदिराजी के बताये मार्ग पर चलनेवालों को फिर कांग्रेस में महत्व दिया जाने लगा है। अभी कमलापति त्रिपाठी केंद्रीय

राहत कमेटी के संयोजक बने हैं। उमाशंकर दीक्षित जैसे अनुभवी नेताओं से पार्टी सलाह लेने लगी है। फिर, राजीव गांधी भी स्वयं इंदिराजी के बताये मार्ग पर चलने लगे हैं।

माया: इसका मतलब, एक साल के अंदर राजीव बदल गये हैं?

प्रणब: इसको इस तरह न कहकर ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिन नये नेताओं ने पार्टी पर कब्जा करना चाहा था, अब उनको दूर हटाया गया है।

माया: विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा है कि बोफोर्स प्रकरण में घूस लेने की नैतिक जिम्मेदारी से राजीव नहीं बच सकते। आपका क्या कहना है?

प्रणब: (मुस्कराकर) रक्षामंत्री के रूप में यह जिम्मेदारी तो उनकी भी है। इसके अलावा ऐसी बात तो नहीं है कि उस समय वे मंत्रिमंडल में नहीं थे। इसलिए मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व से वह भी नहीं बच सकते। फिर विश्वनाथ प्रताप ने तो अनेक प्रकार की बातें कही हैं। उन्होंने बम्बई में कहा था कि बोफोर्स कांड में राजीव शामिल नहीं हैं। फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में कहा कि राजीव उसके उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। ऐसे परस्पर विरोधी बयान का क्या मतलब होता है?

माया: आप क्या महसूस करते हैं कि राजीव बोफोर्स प्रकरण में शामिल हैं?

प्रणब: यह प्रश्न असंगत है। प्रधान मंत्री ने संसद में घोषणा की है कि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य बोफोर्स डील में शामिल नहीं है। संसद भारतीय लोकतंत्र का महापीठ है। वहां कोई झूठ नहीं कह सकता। कम-से-कम प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं संसद की मर्यादा में विश्वास करता हूं। आप लोग भी यह जरूर नहीं चाहते होगें कि कोई भारतीय हर्शमैन या स्वीडिश रेडियो को भारतीय संसद से अधिक विश्वसनीय माने। फिर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने इस संबंध में संसदीय जांच समिति का गठन किया है। इससे सरकार की यही सदिच्छा प्रकट होती है कि वह सचाई को सामने लाना चाहती है। फिर राजीव गांधी ने यह भी कहा है कि विपक्षी दल चाहें, तो स्वीडन में अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

माया: आप तो वित्तमंत्री थे। स्विस बैंक में रुपए जमा करने के मामले में आप किसको जिम्मेदार समझते हैं?

प्रणब: यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ राजनीति करने की मानसिकता लेकर विचार करने से-इसके उत्तर में स्वार्थ की गंध आ सकती है।

माया: लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह तो उसी रुपए का पता लगाने के लिए लड़ाई के मैदान में आये हैं? यहां तक कि जब वे वित्तमंत्री थे, तब भी उन्होंने काले धन के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा था?

प्रणब: प्रधान मंत्री की सहमति के बिना क्या कोई मंत्री अपनी तरफ से कोई निर्णय ले सकता है? मंत्रिमंडल का निर्णय संयुक्त होता है।

माया: फिर क्या आप यही कहना चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ही विश्वनाथ प्रताप सिंह जनजागरण करते फिर रहे हैं?

प्रणब: मैं किसी उद्देश्य से कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। विश्वनाथ प्रताप ने कहा है कि राजनीतिक दलों को व्यवसायियों से पैसा नहीं लेना चाहिए। फिर बताइए, नयी पार्टियों को कहां से पैसा मिलेगा? फिर वह जिन राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं, उनमें कौन ऐसा दल है, जिसने व्यवसायियों से पैसा नहीं लिया? यहां तक कि विश्वनाथ प्रताप के कुछ घनिष्ठ लोगों ने चुनाव के लिए व्यवसायियों से चंदा लिया है?

इंदिरा परिवार का दान भारतवासी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तीन दशकों से उसी परिवार के लोग देश को नेतृत्व दे रहे हैं। कांग्रेस में राजीव का विकल्प नहीं है, तभी तो मैंने इंदिराजी के अचानक दुखद निधन के बाद राजीव को प्रधानमंत्री बनाया था।

माया: आपका संकेत क्या अरुण नेहरू की तरफ है?

प्रणब: मैंने किसी की ओर संकेत करते हुए ऐसा नहीं कहा।

माया: सुनने में आया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में अरुण नेहरू ही पार्टी के लिए धन-संग्रह करते थे। इस कारण वह श्रीमती गांधी के बड़े नजदीकी थे। आपका क्या कहना है?

प्रणब: कोई भी राजनीतिक दल बहुतों के दान से चलता है। अब वह दान कौन लेता था और कौन नहीं, यह प्रश्न गौण है। फिर इंदिराजी के नजदीकी लोगों की बात की जाये, तो यह भी कहना पड़ेगा कि मुझको भी उन्होंने एकदम नीचे से ऊपर उठाया था। उन्हीं के आसपास रहकर मुझे राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली है। लेकिन पार्टी में रहने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है।

माया: आप जो कांग्रेस में लौट रहे हैं, उसके पीछे कौन-सी उम्मीद काम कर रही है?

प्रणब: मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। फिर, किसी तरह की उम्मीद लेकर मैं कांग्रेस में नहीं आया था। कांग्रेस मेरा घर है, कांग्रेस मेरी संस्कृति है। मां के पास शरण मिले, इसके अलावा और कौन-सी उम्मीद हो सकती है?

माया: सुनने में आ रहा है कि फिर मंत्रिमंडल में लिये जाने के बारे में आपको वचन दिया गया है?

प्रणब: वह सब अफवाह है। विभिन्न समाचार पत्रों में देख रहा हूं कि मुझे योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जायेगा। लेकिन इस तरह उपाध्यक्ष नहीं बना जा सकता। अध्यक्ष विभागीय मंत्री होता है। इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है, सरासर अफवाह है।

माया: आपकी राय में विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या भविष्य है?

प्रणब: किसी व्यक्ति का भाग्य बताने लायक ज्योतिषी मैं नहीं हूं। फिर भी इतना कह सकता हूं कि पहले भी देखा गया है कि कांग्रेस के संगठन से बाहर जाकर कोई टिक नहीं सकता। देश में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है।

माया: राजीव का?

प्रणब: इंदिरा परिवार का दान भारतवासी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तीन दशकों से उसी परिवार के लोग देश को नेतृत्व दे रहे हैं। कांग्रेस में राजीव का विकल्प नहीं है, तभी तो

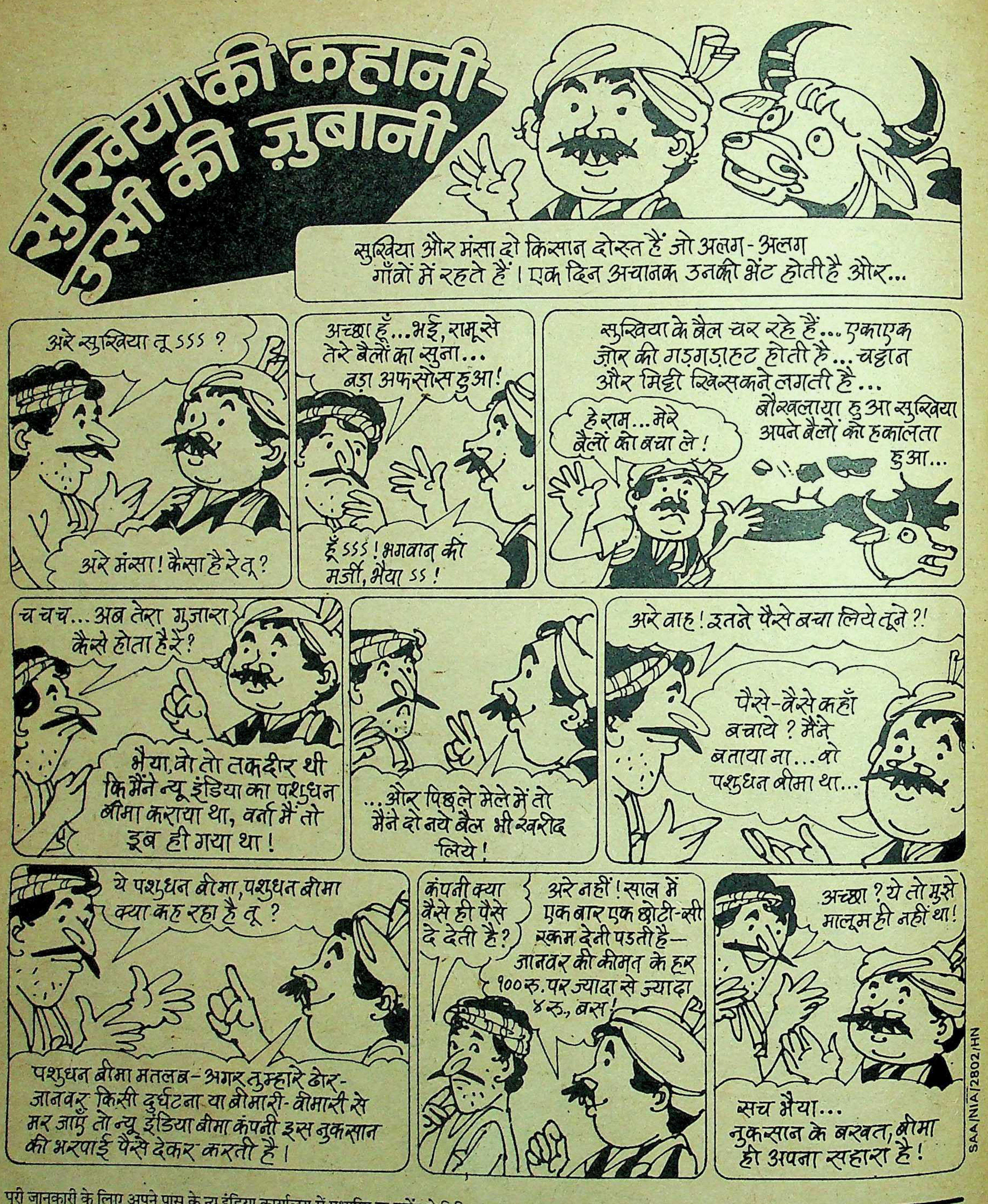
सुखिया की कहानी-
उसी की ज़ुबानी
सुखिया और मंसा दो किसान दोस्त हैं जो अलग-अलग गाँवों में रहते हैं। एक दिन अचानक उनकी भेंट होती है और...
अरे सुखिया तू ऽऽऽ ?
अरे मंसा! कैसा है रे तू?
अच्छा हूँ...भई, रामू से तेरे बैलों का सुना... बड़ा अफसोस हुआ!
हूँ ऽऽऽ! भगवान की मर्ज़ी, भैया ऽऽ!
सुखिया के बैल चर रहे हैं... एकाएक ज़ोर की गड़गड़ाहट होती है... चट्टान और मिट्टी खिसकने लगती है...
हे राम...मेरे बैलों को बचा ले!
बौखलाया हुआ सुखिया अपने बैलों को हकालता हुआ...
च चच... अब तेरा गुजारा कैसे होता है रे?
भैया, वो तो तकदीर थी कि मैंने न्यू इंडिया का पशुधन बीमा कराया था, वर्ना मैं तो डूब ही गया था!
...और पिछले मेले में तो मैंने दो नये बैल भी खरीद लिये!
अरे वाह! इतने पैसे बचा लिये तूने?!
पैसे-वैसे कहाँ बचाये? मैंने बताया ना...वो पशुधन बीमा था...
ये पशुधन बीमा, पशुधन बीमा क्या कह रहा है तू?
पशुधन बीमा मतलब- अगर तुम्हारे ढोर-जानवर किसी दुर्घटना या बीमारी-वीमारी से मर जाएँ तो न्यू इंडिया बीमा कंपनी इस नुकसान की भरपाई पैसे देकर करती है।
कंपनी क्या वैसे ही पैसे दे देती है?
अरे नहीं! साल में एक बार एक छोटी-सी रकम देनी पड़ती है— जानवर की कीमत के हर १०० रु. पर ज्यादा से ज्यादा ४ रु., बस!
अच्छा? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था!
सच भैया... नुकसान के बखत, बीमा ही अपना सहारा है!
SAA/NIA/2802/HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इंडिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

न्यू इंडिया
एश्योरेंस

(जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की
एक सहायक कंपनी)

बीमा — नुकसान में आपका सहारा!

मैंने इंदिराजी के अचानक दुखद निधन के बाद राजीव को प्रधानमंत्री बनाया था।

माया: विपक्षी दल तो राजीव में आस्था रखने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का आरोप मिटाने के लिए राजीव सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।

प्रणब: भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही अगर इस्तीफा देना पड़े, तो आये दिन केंन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को पद-त्याग करना पड़ जाये। मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूं। इसके अलावा क्या विपक्षी दलों की सरकारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप नही हैं? पश्चिम बंगाल की सी०पी०एम० सरकार के नेता ज्योति बसु के विरुद्ध भी तो ऐसे आरोप हैं। उनके राजनीतिक सचिव अशोक बसु के विरुद्ध गबन का आरोप लगाया गया था। इसलिए ज्योति बसु ने क्या इस्तीफा दिया है? उनके बेटे पर भी तो गैरकानूनी ढंग से सुविधा प्राप्त करने का आरोप है। केंद्रीयमंत्री प्रियरंजन ने तो ज्योति बसु की स्विट्जरलैण्ड-यात्रा को लेकर भी आशंका व्यक्त की है। फिर तेलुगुदेशम नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रामाराव के विरुद्ध भी आरोपों की कमी नहीं है। क्या वह भी इस्तीफा देंगे? राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसी मांग की जाती है। फिर जब चाहो तब चुनाव की बात करने पर क्या वह कराया जा सकता है? क्या जनता के पैसे की कोई कीमत नहीं है? जनता ने सरकार को चुना है। वह सरकार पांच वर्ष रहेगी या नहीं, उसका निर्णय संसद लेगी। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि संसद सदस्य यह निर्णय लेंगे। कोई भी ऐरा-गैरा सरकार से इस्तीफे की मांग करे, यह कैसी बात हुई?

माया: विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ मुहम्मद खां क्या ऐरे-गैरे हैं? वे भी तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं?

प्रणब: मैं किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कह रहा हूं। वे अवश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और वह भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, लेकिन उनकी चुनावी विजय के पीछे पार्टी के नेता राजीव गांधी की इमेज (छवि) भी तो एक कारण है?

माया: क्या राजीव ने वह इमेज खो दी है?

प्रणब: कोलंबो-समझौते की सफलता के बाद भी?

माया: आप तो राजीव के पंजाब समझौते का समर्थन नहीं करते। क्या श्रीलंका से समझौते का समर्थन कर रहे हैं?

प्रणब: अवश्य। इससे उत्पीड़ित तमिलों ने चैन की सांस ली है। दूसरी तरफ विश्व में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इसका श्रेय राजीव गांधी को है।

माया: सरकार विरोधी अभियान में कांग्रेस को सी०आई०ए० की साजिश नजर आ रही है। क्या आप यह विश्वास करते हैं?

प्रणब: विदेशी ताकतें हमेशा देश को कमजोर बनाना चाहती हैं। पंजाब हो या असम या त्रिपुरा, सभी जगह विदेशी हाथ होने की आशंका है। सी०आई०ए० अगर भारत को कमजोर बनाने का प्रयास करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है।

माया: फिर तो हर मुद्दे पर आप कांग्रेस हाईकमान और राजीव गांधी के विचारों से सहमत हैं। इससे तो आपका कांग्रेस में लौटना निश्चित है?

प्रणब: मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। कांग्रेस मेरा घर है। इंदिराजी का आदर्श मेरा आदर्श है। उन्हीं का रास्ता मेरा रास्ता है। मैंने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। आज भी नहीं बदल रहा हूं। भविष्य में कभी नहीं बदलूंगा।

—रमाप्रसाद घोषाल

मोच से उसका
अच्छा-खासा दिन खराब क्यों हो?

जब गुणकारी शक्ति आपके हाथ में हो.

आपके स्नेहसिक्त हाथों की प्यार भरी गर्मी और आयोडेक्स की गुणकारी शक्ति – यही तो चाहिए उसको. इसलिए आयोडेक्स हमेशा पास में रखिए. क्योंकि आयोडेक्स में है चोट खायी कोशिकाओं को अच्छा करनेवाला आयोडिन और दर्द दूर करनेवाला मिथाईल सैलिसिलेट.

आयोडेक्स रोजाना दो बार मलें तो दुगना फायदा मिले.

डाक्टरों की सलाह है कि जब तक दर्द जाये नहीं आयोडेक्स रोजाना दो बार मलिए... बल्कि और भी कुछ दिनों तक. क्योंकि दर्द तो केवल बाहरी इशारा है, असली कारण तो है कोशिकाओं की भीतरी चोट.

इसलिए जब भी आपके किसी प्रिय को मोच, पेशियों में खिंचाव, जोड़ों की जकड़न या बदन दर्द की शिकायत हो तो आयोडेक्स मलिए. रोजाना दो बार. फिर तो वे आपका गुण गायेंगे और दुगनी तेजी से काम पर चले आयेंगे.

SKF—एसकेएफ का उत्पादन.

SAA/NIA/2802/HN

आयोडेक्स®
गुणकारी शक्ति से भरपूर खास बाम

विश्वविद्यालय, कालेज ठप्प : शिक्षकों का प्रदर्शन

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

शिक्षकों की हड़ताल

शिक्षक सड़क पर

देश के सभी १५० विश्वविद्यालयों और ५७०० कालेजों के शिक्षकों की हड़ताल एक ऐतिहासिक घटना है। ये शिक्षक मात्र ऊंचे वेतन, तरक्की और बेहतर सेवा शर्तों के लिए ही नहीं लड़ रहे, बल्कि यह आंदोलन नयी शिक्षा नीति की विसंगतियों के खिलाफ भी है। पुनीत टंडन द्वारा शिक्षकों की हड़ताल का जायजा :

४ अगस्त से पूरे देश में शुरू हुई विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों की हड़ताल भारतीय उच्च शिक्षा जगत के इतिहास में घटने वाली अपने किस्म की पहली और अकेली घटना है। यह शायद पहला मौका था, जब हिंदुस्तान के सभी १५० विश्वविद्यालयों तथा ५६०० कालेजों के लगभग दो लाख तीस हजार से भी अधिक शिक्षक एक साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गये। इसी के साथ पूरे देश में उच्चशिक्षण का संपूर्ण तंत्र ठप्प हो गया। विश्वविद्यालय परिसर सूने हो गये और कक्षाएं खाली। इसके कारण पूरे देश में लगभग ३४ लाख से भी अधिक विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई।

संसद भवन के सामने बोट क्लब पर ४ अगस्त को शिक्षकों की हुई विशाल रैली के साथ ही शुरू हुई इस हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने के पीछे कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शिक्षक नेताओं का मानना है कि वे सिर्फ अपने वेतनमानों, और पैसों तथा तरक्की के लिए ही लाखों छात्रों की पढ़ाई बन्द कर सरकार से सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इस हड़ताल को नयी शिक्षा नीति के तहत सरकार द्वारा पूरे शिक्षा जगत को 'गुलाम' बनाने की कथित कोशिश के विरुद्ध अपना संघर्ष मान रहे हैं। शायद यही कारण है कि शिक्षकों की यह हड़ताल जहां एक तरफ शिक्षक और शासन के विरुद्ध एक सीधे संघर्ष का रूप लेती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए शिक्षकों की मांगें मानकर हड़ताल को खतम करवाना कठिन होता जा रहा है। क्योंकि इसका सीधा अर्थ होगा सरकार द्वारा तैयार की गयी नयी शिक्षा नीति की योजना का अपने पहले कदम पर ही लड़खड़ाकर ढह जाना।

विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमान तथा सेवा-शर्तों में सुधार के लिए बनाये गये मेहरोत्रा कमीशन की सिफारिशों में सरकार द्वारा संशोधन कर प्रस्तुत की गयी रपट के बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि शिक्षक और शासन दो विपरीत सिरों पर खड़े हैं। यह टकराव ११ अगस्त, १९८६ को ही साफ नजर आने लगा था जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों को यह जानकारी देने के लिए बुलाया था कि मेहरोत्रा कमीशन द्वारा पेश की गयीं संस्तुतियों में सरकार क्या-क्या संशोधन स्वीकार कर रही है और क्या नहीं। शिक्षक नेता पहले से ही मेहरोत्रा कमीशन से खुश नहीं थे। दिसम्बर, १९८३ में प्रसिद्ध रसायनशास्त्री आर०सी० मेहरोत्रा की अध्यक्षता में गठित कमीशन को शिक्षकों के वेतन तथा सेवा-शर्तों में सुधार संबंधी अपनी रपट देने के लिए दस महीने का समय दिया गया था। किंतु ३० सदस्यीय इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट १० महीने के बजाय २९ महीने में मई १९८६ में पेश की। शिक्षक नेताओं का मानना है कि कमीशन ने जहां एक तरफ उनकी सेवा-शर्तों व वेतन में सुधार के लिए थोड़ी-बहुत संस्तुतियां कीं, वहीं तमाम ऐसी भी सिफारिशें पेश कीं जो शिक्षकों को नागवार गुजरती थीं। किंतु इससे ज्यादा तनाव की स्थिति तब पैदा हुई, जब मेहरोत्रा कमीशन की रिपोर्ट पर १३ महीने तक विचार-विमर्श करने के बाद मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा मंत्रालय ने १७ जून, १९८७ को शिक्षकों के लिए नये वेतनमान के साथ ही नयी सेवा-शर्तों की एक लंबी फेहरिस्त पेश कर दी। इस फेहरिस्त में जहां एक तरफ मेहरोत्रा कमीशन की उन संस्तुतियों को दरकिनार कर दिया गया, जो शिक्षकों के लिए लाभप्रद थीं, वहीं दूसरी तरफ पूरी रपट में भारी रद्दोबदल कर शिक्षकों पर अंकुश लगाने वाली संस्तुतियों को और बढ़ा-चढ़ाकर शामिल कर लिया गया।

काला दस्तावेज : १७ जून को जारी शिक्षकों के नये वेतनमान व संशोधित सेवा-शर्तों के इस आदेश को जहां एक तरफ शिक्षा मंत्रालय नयी शिक्षा नीति की दिशा में एक ठोस कदम मानता है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक इसे पूरे शैक्षणिक जगत को गुलाम बना देने वाले काले दस्तावेज के रूप में देखता है।

नये वेतनमान तथा सेवा-शर्तों की घोषणा करते हुए सरकारी पक्ष का दावा है कि उन्होंने शिक्षकों की तनख्वाह में जबरदस्त उछाल लाकर इतना आकर्षक बना दिया है कि इस पेशे में समाज की श्रेष्ठतम प्रतिभाएं खिचकर चली आयेंगी तथा शिक्षण-जगत से प्रतिभा के पलायन को बंद किया जा सकेगा, जबकि शिक्षकों का मानना है कि १४ वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद उनके वेतन में सरकार द्वारा की गयी बढ़ोत्तरी खुद सरकार द्वारा महंगाई में हुई बढ़ोत्तरी के आंकड़ों को देखने पर बढ़े हुए दामों की सिर्फ ६४ प्रतिशत क्षतिपूर्ति करती है। शिक्षकों का इस आधार पर यह कहना है कि १४ साल में हुई इस बढ़ोत्तरी के बावजूद जो वास्तविक वेतन अब शिक्षकों को मिलेगा, वह १४ साल पूर्व मिलने वाले वेतन की वास्तविक क्रयक्षमता से ३६ प्रतिशत कम ही होगा। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इसके बावजूद सरकार ने

जनसंचार माध्यमों के माध्यम से इतना झूठा प्रचार किया है कि शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि करके सरकार ने जैसे उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ दे दिया है।

असंतोष का कारण : लेकिन वेतन वृद्धि से ज्यादा जिस मुद्दे पर शिक्षक समुदाय में असंतोष व्याप्त है, वह है उनकी सेवा-शर्तों में किया जाने वाला परिवर्तन। इसके तहत शिक्षकों के पहले से चले आ रहे तीन ग्रेड (वेतनमानों) को बढ़ाकर सात ग्रेड कर दिया गया है। पहले लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसर के तीन ग्रेड हुआ करते थे लेकिन उनकी जगह अब लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, सलेक्शन ग्रेड लेक्चरर, रीडर, सीनियर स्केल रीडर, प्रोफेसर तथा प्रोफेसर विशिष्ट के सात ग्रेड बना दिए गये हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति तय की गयी है कि ग्रेडों को घटाया जाय तथा राष्ट्रीय वेतन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर हर नौकरी में ग्रेडों की संख्या घटाकर लगभग एक तिहाई कर दी है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के मामले में सरकार ने यह उलटी नीति अपनायी है।

शिक्षकों के नये ग्रेड़ के अंतर्गत उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। पहले १९७३ में लागू की गयी नीति के तहत शिक्षकों की सहज रूप से पदोन्नति हो जाती थी। शिक्षण-जगत में व्याप्त जड़ता को देखते हुए १९७३ में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि शिक्षकों के अनुभव तथा कार्यकाल को देखते हुए उन्हें लेक्चरर से रीडर तथा रीडर से प्रोफेसर के पदों पर उन्नति दे दी जाए। लेकिन नयी सेवा-शर्तों में पदोन्नति का वह सहज मार्ग बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शिक्षकों की चुनौती नामक दस्तावेज में कहा गया है कि 'शिक्षकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर नहीं होता इसलिए काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति इस व्यवसाय में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें न तो ठीक-ठीक योग्यता होती है और न शिक्षा देने की प्रवृत्ति।' शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसी धारणा के आधार पर अब यह नीति बनायी गयी है कि शिक्षक के नौकरी में प्रवेश से लेकर पूरे कार्यकाल के दौरान लगातार उसके कार्य, योग्यता, चरित्र का हर साल चार स्तरों पर मूल्यांकन किया जाये। इस मूल्यांकन योजना का यद्यपि अभी तक शिक्षा मंत्रालय ने ठोस प्रारूप पेश नहीं किया लेकिन मोटे तौर पर हर साल एक शिक्षक के विषय में उस शिक्षण संस्थान का प्रमुख, विभागाध्यक्ष, शिक्षक स्वयं अपने विषय में स्वमूल्यांकन तथा छात्र द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन करने की योजना है। इसमें विभागाध्यक्ष एक अतिरिक्त गोपनीय सालाना रपट भी पेश करेगा। इन मूल्यांकनों के आधार पर ही शिक्षक की नौकरी का भविष्य, वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति तय होगी।

शिक्षक इस सालाना मूल्यांकन पद्धति की नयी व्यवस्था से बेहद क्षुब्ध हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुरली मनोहर प्रसाद सिंह का मानना है कि शासन इस प्रक्रिया को लागू करके शिक्षकों को अपना तथा मैनेजमेंट की जी-हुजूरी करने वाला गुलाम बनाना चाहता है। उनका कहना है कि शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज है उसकी स्वतंत्रता और एक भयमुक्त माहौल। इसके बिना कोई भी बौद्धिक चिन्तन व शोध संभव नहीं। इस पद्वति के लागू होने के बाद शिक्षक के सिर पर सदैव एक नंगी तलवार लटकी रहेगी। वह कोई भी ऐसी बात कहने, सोचने और लिखने को स्वतंत्र नहीं होगा जो शासक वर्ग को नागवार गुजरे। निश्चय ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्च शैक्षणिक संस्थाएं विश्वविद्यालय व अनुसंधान केन्द्र ही समाज के वह केन्द्र होते हैं, जहां बुद्धिजीवीवर्ग सामाजिक व्यवस्था, अर्थनीति, न्यायव्यवस्था, शासनतंत्र से लेकर संविधान और राजनैतिक दर्शन पर स्वतंत्र होकर गहन चिन्तन और शोध कर सकता है। उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को निर्भय हो पेश कर सकता है तथा विभिन्न विपरीत विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। समाज के बौद्धिक वर्ग की यही भूमिका उस समाज की प्रगति और जीवन्तता को गति देती है। किंतु नयी सेवा-शर्तों के अधीन क्या शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाओं की यह स्वाधीनता व स्वायत्तता कायम रह पायेगी? निश्चय ही यह ऐसा गंभीर प्रश्न है, जिसने जहा एक तरफ शिक्षकों की इस हड़ताल को एक सामान्य ट्रेड यूनियन आंदोलन से अलग कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ शासन तथा नौकरशाही द्वारा समाज की 'स्वतंत्र मनीषा' पर अंकुश लगाये जाने की कोशिश के विरुद्ध एक जेहाद का रूप ले लिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के भूतपूर्व महामंत्री तथा समाजवादी चिन्तक आनन्द कुमार का "माया" से कहना था कि हमारे आंदोलन का चरित्र सिर्फ ज्यादा वेतन की मांग करने वाली किसी हड़ताल का चरित्र नहीं बल्कि बहुत धीमे-धीमे इस देश में शिकंजा फैलाती जा रही एक नव फासीवाद के विरुद्ध एक समाज के बौद्धिक वर्ग की लड़ाई है जो चिन्तन, विचार, शिक्षा की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सुधांशु पचौरी तो इस मुद्दे पर और भी स्पष्ट हैं। उनका मानना है कि शिक्षकों की इस ऐतिहासिक हड़ताल के बीज उसी दिन बो दिए गये थे जब नयी शिक्षा नीति की घोषणा की गयी थी। वह मानते हैं कि शिक्षकों की इस लड़ाई का मुख्य मुद्दा ज्यादा पैसा हासिल करना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान हासिल करना है।

१७ जून को जारी शिक्षकों के नये वेतनमान व संशोधित सेवा शर्तों के इस आदेश को जहां एक तरफ शिक्षा मंत्रालय नयी शिक्षा नीति की दिशा में एक ठोस कदम मानता है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक इसे पूरे शैक्षणिक जगत को गुलाम बना देनेवाले काले दस्तावेज के रूप में देखता है।

राष्ट्रीय एकता के लिए घातक : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुरली मनोहर जहां एक तरफ अपनी मांगों के समर्थन में ठोस और व्यापक सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी मानना है कि सरकार द्वारा लागू की गयी नयी सेवा-शर्तें समाज में पहले से मौजूद विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, भाषायी तनावों को और ज्यादा गहरा करेंगी, तथा राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचानेवाली साबित होंगी। इस संदर्भ में वह शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित नयी नीति पर तीखा हमला करते हैं। नयी नीति के तहत यह प्रावधान है कि अब राष्ट्रीय प्रशासकीय सेवाओं के तरीके से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिए एक सम्मिलित केन्द्रीय परीक्षा के तहत नौकरियां दी जायेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक विश्वविद्यालय के एक विभाग से यदि किसी लड़के ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं तो पहले यदि वहां नौकरी खाली हो तो उस छात्र को यह मौका मिल जाता था कि वह उस विभाग में पढ़ाये। किंतु अब केन्द्रीय परीक्षा में जो छात्र पास होंगे, वहीं वे ही शिक्षक होंगे। ऐसी स्थिति में विभाग विशेष द्वारा स्नातकोत्तर कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने या विशेष योग्यता अंक प्राप्त करने आदि का कोई स्थान नहीं रह जाता। शिक्षण को छोड़कर शेष अन्य नौकरियों में पहले से ही ऐसी व्यवस्था लागू होने के कारण विश्वविद्यालय की उच्च डिग्री व अंकों का महत्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसका एकमात्र महत्व शिक्षण क्षेत्र में बचा था, जो अब इस व्यवस्था से समाप्त हो जायेगा।

सैद्धांतिक मुद्दे : इसके साथ ही इस व्यवस्था के तहत उठने वाली अन्य समस्याएं और भी ज्यादा गंभीर तथा सैद्धांतिक मुद्दों से जुड़ी हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों में एक ही विषय को लेकर अलग-अलग वैचारिक दृष्टियों तथा 'एप्रोच' से अलग-अलग जगह शोध व अध्यापन होता है। विशेषकर समाजशास्त्रीय विषयों में उदाहरण के लिए यदि एक विश्वविद्यालय में इतिहास को पढ़ाने तथा व्याख्यायित करने के संदर्भ में आधुनिक दृष्टि प्रचलित है तो दूसरे में इतिहास को परंपरागत दृष्टि से व्याख्यायित किया जाता है। यहां तक कि भाषाओं के मामले में भी यदि एक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की स्नातकोत्तर कक्षा में काव्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के भाषाशास्त्र पर। केन्द्रीय स्तर पर एक परीक्षा द्वारा शिक्षकों

की भर्ती होने की स्थिति में पूरे देश के छात्र विषय विशेष की एकमात्र उसी दृष्टि (एप्रोच) से अध्ययन करना पसन्द करेंगे जो केन्द्रीय परीक्षा समिति पर हावी लोगों की दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में शिक्षा के विषयों की अलग-अलग अन्य एप्रोचों (दृष्टि) के स्कूल के छात्र जहां शिक्षक नहीं बन पायेंगे वहीं दूसरी तरफ पूरे देश की शिक्षण-व्यवस्था में उस विषय के उसी दृष्टि वाले अध्यापकों का वर्चस्व कायम रहेगा, जिसे शासक वर्ग चाहेगा। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ विषयों के अन्य स्कूल धीमे-धीमे समाप्त हो जायेंगे, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कानून, इतिहास तथा समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति होने पर पूरे समाज के बौद्धिक विकास तथा स्वतंत्र चिन्तन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा। क्योंकि इन सभी विषयों में अलग-अलग दृष्टियों स्कूलों व चिन्तन परंपराओं की विविधता ही बौद्धिक जगत के विकास की पहली और बुनियादी शर्त है। निश्चय ही नयी सेवा-शर्तों व नियुक्तियों के नये ढांचे का विरोध करने वाले शिक्षक एक-तरफ इन व्यापक और विराट मूल्यों के प्रति सचेत हैं किंतु शिक्षकों की हड़ताल की जीवन्तता तथा और जुझारू पैनापन देने में जो तर्क ज्यादा असर कर रहा है, वह एक तरफ या तो उनकी आर्थिक मांगे हैं, या दूसरी तरफ उनकी पदोन्नति के बन्द होते रास्ते से पैदा होती कुंठाएं। इसके साथ ही शिक्षकों के आत्मस्वाभिमान को जिस बात ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचायी है, वह है उनके तथा प्रशासनिक अधिकारियों (आई०ए०एस०) की वेतन वृद्धि व अन्य सुविधाओं में भारी अन्तर। इस संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सुधीर गोयल का कहना था कि एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रति वर्ष छह हजार रुपए की राशि विशेष भुगतान के रूप में बौद्धिक विकास के लिए दी जाती है। मेहरोत्रा कमीशन ने शिक्षकों के बौद्धिक विकास के लिए केवल दस हजार रुपए देने की मांग की थी। किंतु सरकार ने उसको पूरे तरीके से इनकार कर दिया। इसी प्रकार शिक्षकों द्वारा किये गये शोधकार्य के लिए किये जाने वाले खर्च पर भी किसी प्रकार की कोई धनराशि देना सरकार ने मंजूर नहीं किया। उनका तर्क था कि जहां एक तरफ सरकार शिक्षकों के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं देने को तैयार नहीं है। मेहरोत्रा कमीशन ने उन शिक्षकों के लिए यातायात भत्ता देने की भी संस्तुति की थी, जिन्हें परिसर में मकान नहीं मिले हैं। किंतु सरकार ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इस प्रकार की शिकायतों की एक लंबी फेहरिस्त हाथ में लिए शिक्षक आंदोलनरत हैं। प्रदर्शन, धरना, हड़ताल के बाद वह जेल भरो आंदोलन में जुटे हैं।

शिक्षकों की इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व कर रहे विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षक संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के महासचिव मृण्मय भट्टाचार्य यह दावा करते हैं कि सरकार के तमाम दबाव के बावजूद वह अपनी लड़ाई को उस समय तक जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। मुरली मनोहर सिंह का कहना है कि एक ओर जहां जगह-जगह पर प्रबंधक शिक्षकों पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर दबाव डाल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सदन में शिक्षा-मंत्री झूठे बयान देकर देश को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं ने इस हड़ताल को पुरजोर समर्थन देना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जिन-जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वहां यह कोशिश शुरू हो गयी है कि राज्य के स्तर पर शिक्षकों की इन मांगों को मानकर केन्द्र सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी जाये। पं० बंगाल में वामपंथी दलों की संयुक्त समिति ने जहां एक तरफ शिक्षकों की इन मांगों को वाजिब मानते हुए उनका पूरा समर्थन करने का पूरा फैसला किया है, वही मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए शिक्षक नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। इसी प्रकार देवीलाल तथा एन०टी० रामाराव ने भी शिक्षकों की इस लड़ाई को समर्थन देने तथा शिक्षकों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

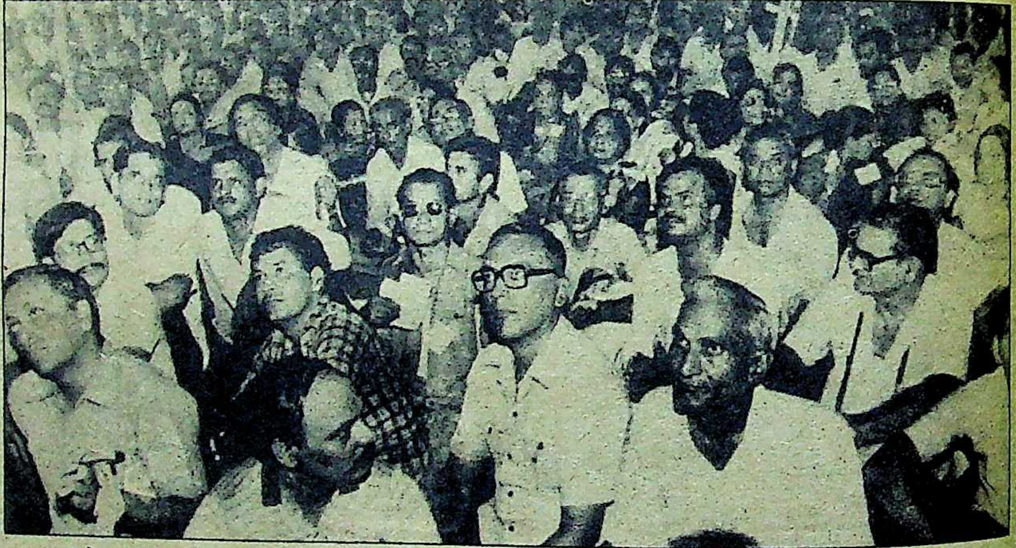

सरकार को झुकाने पर आमादा : एक सभा में शिक्षक

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

दिलचस्प पहलू : शिक्षकों की इस लड़ाई में नजर आने वाला जो दिलचस्प पहलू है, वह है शिक्षकों के साथ छात्रों का पूरा समर्थन। इसके बावजूद कि शिक्षकों की इस हड़ताल से जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, वह छात्र ही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अंजना राजनीतिशास्त्र में एम०फिल० कर रही हैं। अपने अध्यापक शमसुलस्लाम के साथ शिक्षकों की सभाओं में नुक्कड़ नाटक कर हड़ताल के समर्थन में जनमत जुटाने वाली अंजना का मानना है कि शिक्षकों की हड़ताल से छात्रों का नुकसान नहीं क्योंकि शिक्षक जिस नयी नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके शिकार शिक्षक तथा छात्र समान रूप से होंगे। ऐसे भी छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में आने के बाद दिन भर खाली हाथ बिना पढ़े-लौट जाने के बाद इस बात से क्षुब्ध हैं कि शिक्षकों के कारण उनका नुकसान हो रहा है। शिक्षकों की इस हड़ताल से निकलकर आने वाला जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक तथ्य है, वह है आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के मुकाबले महिला शिक्षिकाओं की ज्यादा भागीदारी और संख्या। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर विरोध प्रकट करने वाली दैनिक बैठकों में पुरुष शिक्षकों के मुकाबले शिक्षिकाओं की ज्यादा संख्या इसका ठोस प्रमाण है। इसका कारण जहां एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की संयुक्त मंत्री शाश्वती मजूमदार द्वारा महिला शिक्षकों में पिछले दिनों किया गया व्यापक कार्य है, वहीं दूसरी तरफ महिला शिक्षिकाओं में बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना है। सास्वती मजूमदार यह मानती हैं कि महिला शिक्षिकाओं पर पुरुषों के मुकाबले परिवार से यह दबाव ज्यादा रहता है कि वे हड़ताल में सक्रिय योगदान न दें या सीधे संघर्ष में न उतरें। फिर भी संघर्ष में उनकी भागीदारी इस चीज का सबूत है कि शिक्षक हड़ताल के मुद्दे इतने व्यापक और महत्वपूर्ण हैं कि समाज के हर हिस्से से इसे समर्थन मिलना स्वाभाविक है। शायद इसी सोच के तहत शिक्षक नेताओं ने अब यह भी अभियान शुरू कर दिया है कि वह अपनी लड़ाई में कर्मचारियों तथा छात्रों के साथ अभिभावकों की भी सहानुभूति हासिल करें क्योंकि उनका मानना है कि शायद यह संघर्ष अभी लंबा चलेगा। और ऐसी स्थिति में उन पर सरकार द्वारा पड़ने वाले दबाव से ज्यादा गंभीर दबाव होगा, छात्रों और अभिभावकों का दबाव, जिसके आगे टिक पाने के लिए आवश्यक है कि वह अपनी लड़ाई के मुद्दे उन तक विस्तार से पहुचाएं और उसमें छात्रों का हित भी शामिल करें। इस संदर्भ में उनकी यह भी योजना है कि यदि लड़ाई लंबी चली तो वह हड़ताल पर होते हुए अलग से छात्रों को पढ़ायेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर शिक्षक नेताओं में मतभेद है।

कारण
की इस
ज्यादा
में पुरुष
तों की
विद्या-
प्रकट
कों के
का ठोस
दिल्ली
शाश्वती
नी दिनों
तरफ
जनैतिक
मानती
षों के
रहता है
या मीड़
ी भागी-

श्रीवास्तव

हड़ताल
समाज
भाविक
ताओं ने
कि वह
के साथ
क्योंकि
ी लंबा
सरकार
दबाव
जिसके
अपनी
एं और
संदर्भ
ई लंबी
छात्रों
नेताओं

लिम्का सितारों के लिये लिम्का परवानों के लिये

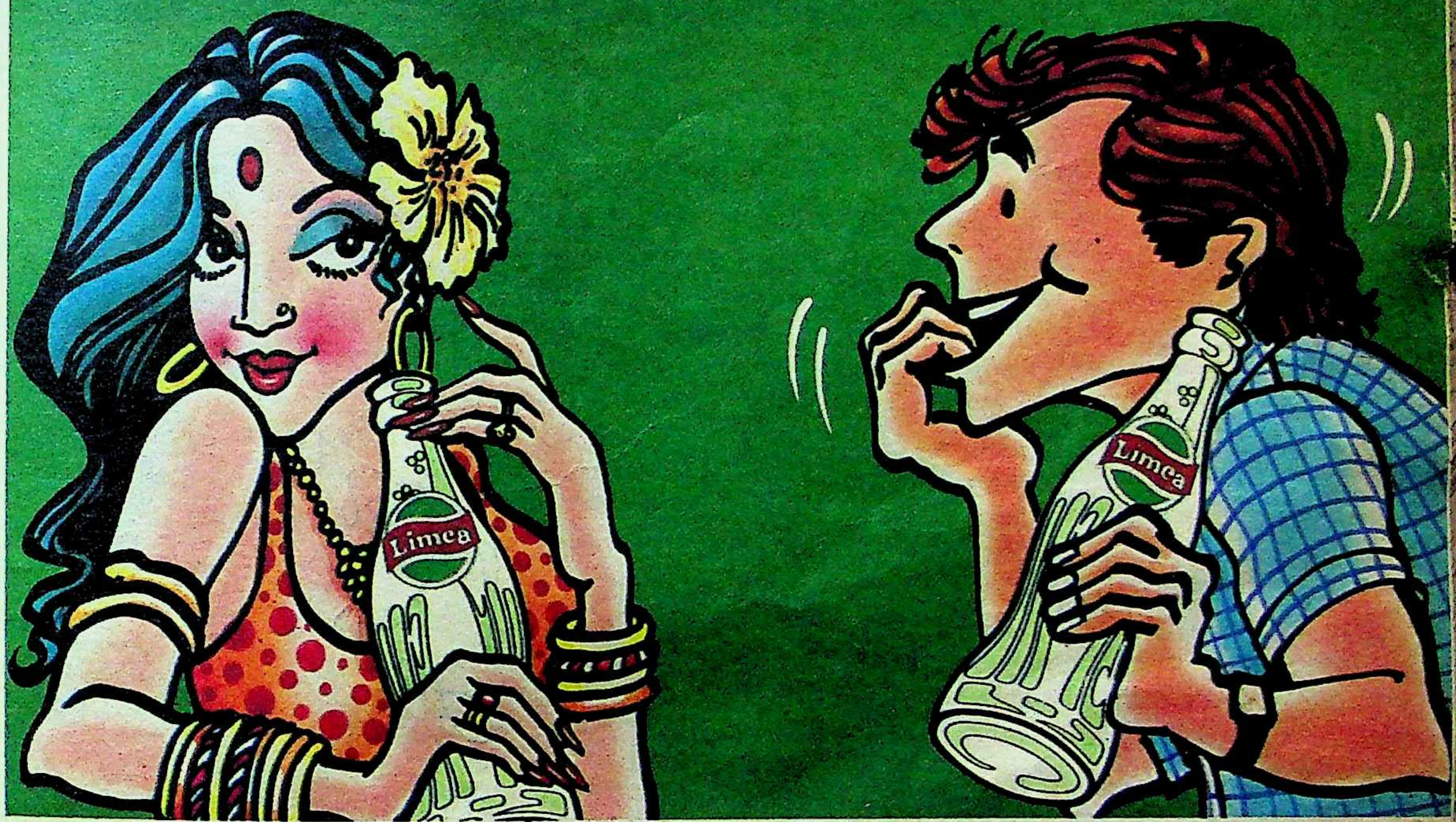

जब आप अपने परवानों की भीड़ से बच निकलने या फिर अपने मनपसंद सितारे की झलक पाने की कोशिश करते-करते थक कर बेहाल हो जायें तो किटाणुरहित लिम्का की बोतल उठायें और अपनी प्यास बुझायें. लिम्का में है आइसोटॉनिक नमक आपकी प्यास बुझाने के लिये.

Limca

नींबू जल-सा मज़ेदार पेय

ठंडा बर्फीला पिएं-पिलाएं

विद्रोहियों के चाणक्य

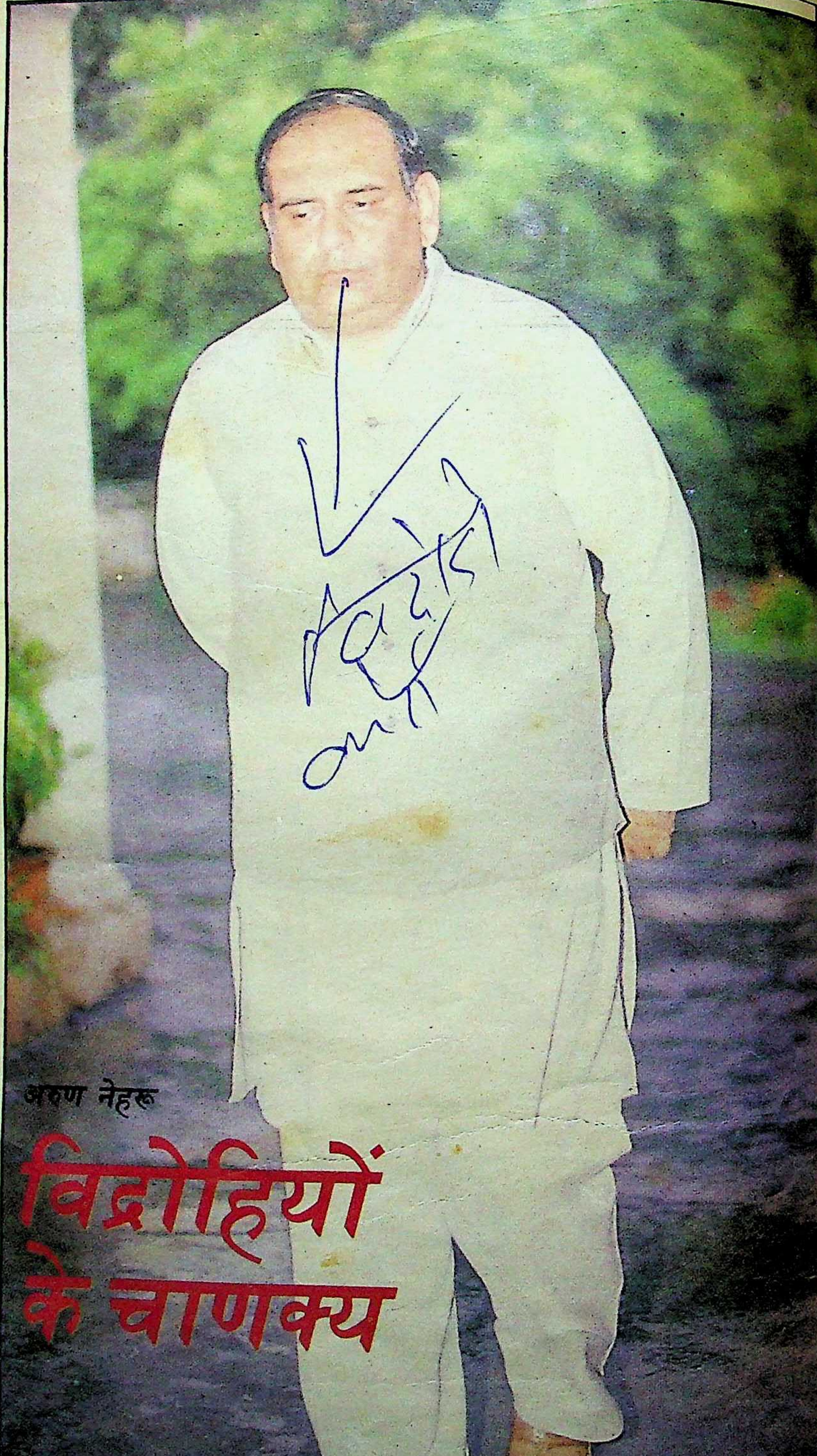

अरुण नेहरू

३१ अक्तूबर, १६८४। राष्ट्रपति भवन का अशोक हाल। प्रधानमंत्री के शपथ-ग्रहण की प्रतीक्षा हो रही है। लेकिन किसी को नहीं पता कि शपथ कौन लेगा? हां, वहां बैठे सदस्य यह जरूर देख रहे हैं कि परदे के पीछे से अरुण नेहरू झांकते हैं और विजय शंकर त्रिपाठी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और फिर श्री त्रिपाठी लपक कर फोतेदार के कान में कुछ कहते हैं। करीब सात बजे राजीव गांधी शपथ-ग्रहण करते हैं—और इसके बाद सभी के मन में यह बात जम जाती है कि राजीव गांधी को उनकी मां का उत्तराधिकारी बनाने में उनके ममेरे भाई (अरुण नेहरू) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

इस योजना के पीछे भी अरुण नेहरू का ही दिमाग माना जाता है कि उस दिन ज्योंही राष्ट्रपति जैल सिंह का विमान हवाई अड्डे को छुए, आर०के० धवन और फोतेदार उस पर चढ़ें और आर०के० धवन राष्ट्रपति को राजीव गांधी के पक्ष में तैयार करें तथा फोतेदार इस बात को देखें कि धवन ऐसा कर रहे हैं या नहीं।

वही नेहरू आज उस खेमे में हैं जो यह कोशिश कर रहा है कि उन्होंने ३१ अक्तूबर को जो किया था, उसे नेस्तानाबूद कर दिया जाये। आज राजीव गांधी के खिलाफ चल रही मुहिम के पीछे मुख्य रूप से अरुण नेहरू का ही दिमाग माना जाता है। उन्हें विद्रोहियों का चाणक्य कहा जा रहा है। क्या कारण है कि जो अरुण नेहरू राजीव गांधी के इतने करीब थे, आज वही उनको सत्ताच्युत करने के अभियान का जी-जान से संचालन करने में लगे हैं।

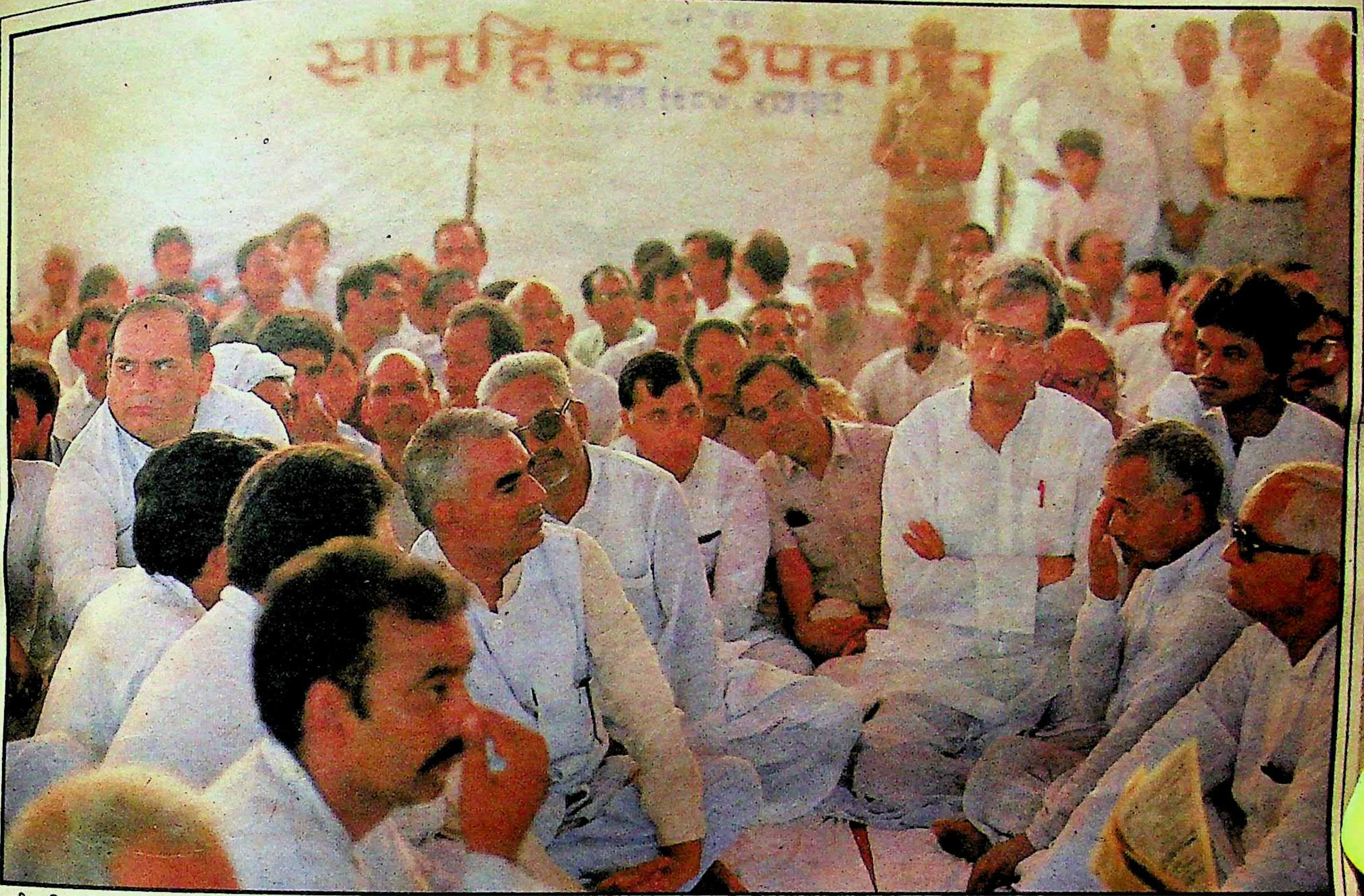

नयी छवि बनाने का उपक्रम: इंका विद्रोही महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर सामूहिक उपवास करते हुए

छाया: सुनील सक्सेना

वह वास्तव में अद्भुत दृश्य था। ९ अगस्त को राजघाट के लान में करीब १५० लोग १२ घंटे के अनशन पर बैठे थे। सूरज आग उगल रहा था और इन सबके बीच मोटी खादी के कुर्ते-पायजामे में अरुण नेहरू ऐसे नजर आ रहे थे मानो वह पक्के गांधीवादी सत्याग्रही हों। जिन लोगों ने उन्हें सफारी सूट पहने १९८२ के एशियाड खेलों की व्यवस्था में ताबड़तोड़ भागदौड़ करते या १९८५ में आतंरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आसपास ब्लैक कैटों को दर्प से आदेश देते देखा है, उनके लिए अरुण नेहरू का यह सर्वथा नया रूप है।

अरुण नेहरू मई, १९८६ में श्रीनगर में हुए हृदयाघात के बाद से राजनीति के अंधेरे में हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की परंपरा के अनुसार ही जोड़तोड़ की राजनीति में संलग्न होना भी नये नेहरू की नियति बन गयी है। यह नया नेहरू उस नेहरू से कहीं अधिक खतरनाक है जो कंप्यूटर के पीछे बैठा करता था और जो नौकरशाह वृत्ति के कांग्रेस-महासचिवों पर कांग्रेस कार्यालय २४, अकबर रोड में बरस पड़ता था। १७ महीनों से वीरानी में रहनेवाले अरुण नेहरू ने संजय गांधी के समान अपनी राजनीतिक कुशलता को धारदार बना लिया है। राजीव गांधी का यह ममेरा भाई एक समय उनका अंतरंग सहयोगी था, लेकिन आज वह उनका कट्टर शत्रु बन चुका है और अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए कृतसंकल्प है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अब दोनों के बीच शांति और समझौते की सब संभावनाएं समाप्त हो गयी हैं।

संधि असंभव: राजीव गांधी द्वारा नेहरू को निष्कासित किये जाने के कुछ सप्ताहों पूर्व कांग्रेस-इ के एक सांसद ने दोनों ममेरे भाइयों में सुलह कराने की कोशिश की थी। नेहरू कुछ मुलायम भी पड़े थे, क्योंकि वह आमने-सामने बैठकर मतभेदों को दूर करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन बताया जाता है कि राजीव गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे—शायद वह अपने ममेरे भाई से बेहद नाराज थे। बताया जाता है कि उन्होंने उक्त सांसद से साफ-साफ कह दिया था कि उन्हें अरुण नेहरू से कुछ लेना-देना नहीं है। राजीव गांधी के मन में नेहरू के प्रति इतना जहर देखकर वह सांसद सकते में आ गये, लेकिन राजीव गांधी के निकटस्थ सहयोगी रहे एक पुराने मित्र को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनका कहना है कि अपनी मां के विपरीत राजीव गांधी कभी झुकते नहीं, वह इसे कमजोरी का ऐसा चिन्ह मानते हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक दृष्टि से भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल, नेहरू और गांधी के बीच दिसंबर, १९८५ से ही मतभेद उभरने के लक्षण नजर आने लगे थे, लेकिन जब से दिल्ली में अर्जुन सिंह राजीव गांधी के सलाहकार बने और नेहरू के आदमी के रूप में प्रसिद्ध आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी के नेतृत्व के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया है, तब से दोनों के मतभेद इस हद तक पहुंच चुके हैं कि समझौते के कोई आसार नजर नहीं आते।

पहला वार नेहरू पर: यह एक रोचक तथ्य है कि राजीव गांधी ने हमेशा वी०पी० सिंह से पहले अरुण नेहरू पर चोट की। गत वर्ष नवंबर में मंत्रिमंडल से पहले अरुण नेहरू हटाये गये, जबकि वी०पी० सिंह कुछ मास और खिंचे। इस जुलाई में भी यही हुआ। नहरू को वी०पी० सिंह से पहले कांग्रेस-इ से निष्कासित किया गया। कुछ प्रमुख कांग्रेसी इसका कारण यह बताते हैं कि शिवशंकर, बूटा सिंह, एम०एल० फोतेदार, अर्जुन सिंह और गोपी कृष्ण अरोडा—आदि राजीव गांधी के अधिकांश सलाहकार घोर नेहरू विरोधी हैं। मतभेद नीतियों को लेकर ही नही हैं, बल्कि इन सबको लगता है कि अरुण नेहरू ने उनके 'अहं' को ठेस पहुंचायी है, इसलिए टकराव अहं का भी है। क्योंकि ये सब अरुण नेहरू को राजनीति में अपने से छोटा मानते रहे हैं, लेकिन कम-से-कम फोतेदार ऐसा दावा नहीं कर सकते। भले ही अरुण नेहरू लखनऊ के हों और फोतेदार अनंतनाग के, फिर भी दोनों कश्मीरी हैं और जम्मू व कश्मीर के मामलों में दोनों एक दूसरे के काफी निकट रहे हैं।

लेकिन बताया जाता है कि जनवरी, १९८६ से फोतेदार ने अपने स्वभावतः रहस्यमय अंदाज में नेहरू के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ७, रेसकोर्स रोड में हवा का रुख पलट रहा है। राजीव गांधी बीमार नेहरू की मिजाजपुरसी के लिए श्रीनगर नहीं गये और जब किसी ने इस पर सवाल किया, तो बड़ी सहजता से यह कह दिया गया, "साहिब (राजीव) उनसे मिलने इसलिए नहीं गये, क्योंकि वह समझते थे कि इससे नेहरूजी के स्वास्थ्य लाभ में कहीं देरी न हो।" तब साहिब और फोतेदार अपनी इस आत्मीय प्रतिक्रिया से कुछ लोगों को अंधेरे में रखने में सफल हो गये थे। स्वयं अरुण नेहरू को भी तब तक इस बात का अहसास नहीं था कि रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। इसका अहसास तो उन्हें श्रीनगर से दिल्ली आने पर हुआ। जब वह राजीव गांधी से मिले, तो बातों की शुरुआत आत्मीय ढंग से नहीं हुई। तभी उन्हें लगा कि दोनों के संबंधों में गंभीर दरार पड़ चुकी है।

कोई नहीं जानता कि इसका असली कारण क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी समय राजीव गांधी ने ऐसा अवश्य महसूस किया होगा कि अरुण नेहरू का रुतबा जरूरत से ज्यादा नाकाबिले-बर्दाश्त बढ़ गया है। पंजाब की वर्तमान दुर्दशा के लिए भी अरुण नेहरू पर उंगली उठायी गयी। यह समझा जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर पंजाब में कठोर रुख अपनाया गया और इसी कारण पंजाब अब भी झुलस रहा है। कहा तो यह भी गया कि जब राजीव गांधी पंजाब और कश्मीर की समस्याओं से जूझ रहे थे, उस दौरान अरुण नेहरू ने बड़ी चतुराई से वीरबहादुर सिंह, हरिदेव जोशी, एस०बी० चह्वाण, मोतीलाल वोरा और जी०एम० शाह को मुख्यमंत्री बना दिया। जे०बी० पटनायक, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भजनलाल भी अरुण नेहरू के आदमी बताये जाते हैं। इन चर्चाओं के बीच हर नेता को लग सकता था कि अरुण नेहरू सारी सत्ता अपने हाथों में भींचते चले जा रहे हैं। इस आशंकित सुनियोजित विद्रोह ने ही अरुण नेहरू के निष्कासन के लिए उकसाया।।

दूसरी ओर वी०पी० सिंह के बारे में यह माना गया कि वह अकेले हैं, पार्टी में कोई खुलकर उनके समर्थन में आगे नही आयेगा। इसलिए वह राजीव गांधी के नेतृत्व को कभी चुनौती नहीं देंगे। यही वजह थी कि अरुण नेहरू को मंत्रालय और पार्टी से निष्कासित करने में फुर्ती दिखायी गयी। बस राजीव गांधी के सलाहकार यहीं मात खा गये। वीर बहादुर सिंह ने पं० नेहरू के बाद के निष्ठाहीन कांग्रेस-इ नेताओं का अनुकरण करते हुए अपनी निष्ठा बदलकर अरुण नेहरू से खुद को अलग करने में देर नहीं लगायी। अब अरुण नेहरू, वी०पी० सिंह के साथ जनसभाओं में भाग ले रहे हैं, वह राजीव गांधी के नेतृत्व को चुनौती देनेवालों के साथ आम जनता से संपर्क कर रहे हैं। अचानक सारे समीकरण बदल गये। एक ममेरा भाई नैतिकतावादियों की ओर चला गया और दूसरा ममेरा भाई राजीव ऐसे लोगों के बीच अकेला नजर आने लगा जो लोभी और सत्ता के भूखे माने जाते हैं।

बड़ा खतरा : भले ही सिंह और नेहरू के आपसी मतभेद कितने ही उग्र क्यों न माने जाते हों, लेकिन इन दोनों का मिलन उस खतरे से भी बड़ा खतरा बन सकता है, जिसकी आशंका मुख्यमंत्रियों की ओर से की जाती थी। बताया जाता है कि शिवशंकर और बूटा सिंह की सलाह पर वी०पी० सिंह के साथ अरुण नेहरू को निष्कासित करने का गलत कदम उठा लिया गया। यद्यपि राजीव गांधी के सलाहकारों ने यह सोचा होगा कि वी०पी० सिंह के साथ मिलने से अरुण नेहरू की ही छवि धूमिल होगी, लेकिन वे भूल गये कि पिछले तीन महीनों में खासकर मार्च के बाद से, तो राजीव गांधी के लिए मौसम बेहद गर्म हो गया है। विदेश में भारतीय धन, स्विट्जरलैण्ड में बच्चन के बसने आदि की चर्चाएं लोगों की जुबान पर इस कदर छायी रही हैं कि दो-ढाई साल पहले के अरुण नेहरू के किस्सों पर ध्यान देने की फुरसत किसे है। आज राजीव गांधी के समर्थकों की छवि शायद ही वैसी साफ हो, जैसा कि दावा किया जाता है। अब अरुण नेहरू व्यंग्यपूर्वक कह सकते हैं कि वह कभी ब्रसेल्स और जेनेवा नहीं गये, जबकि हर कोई

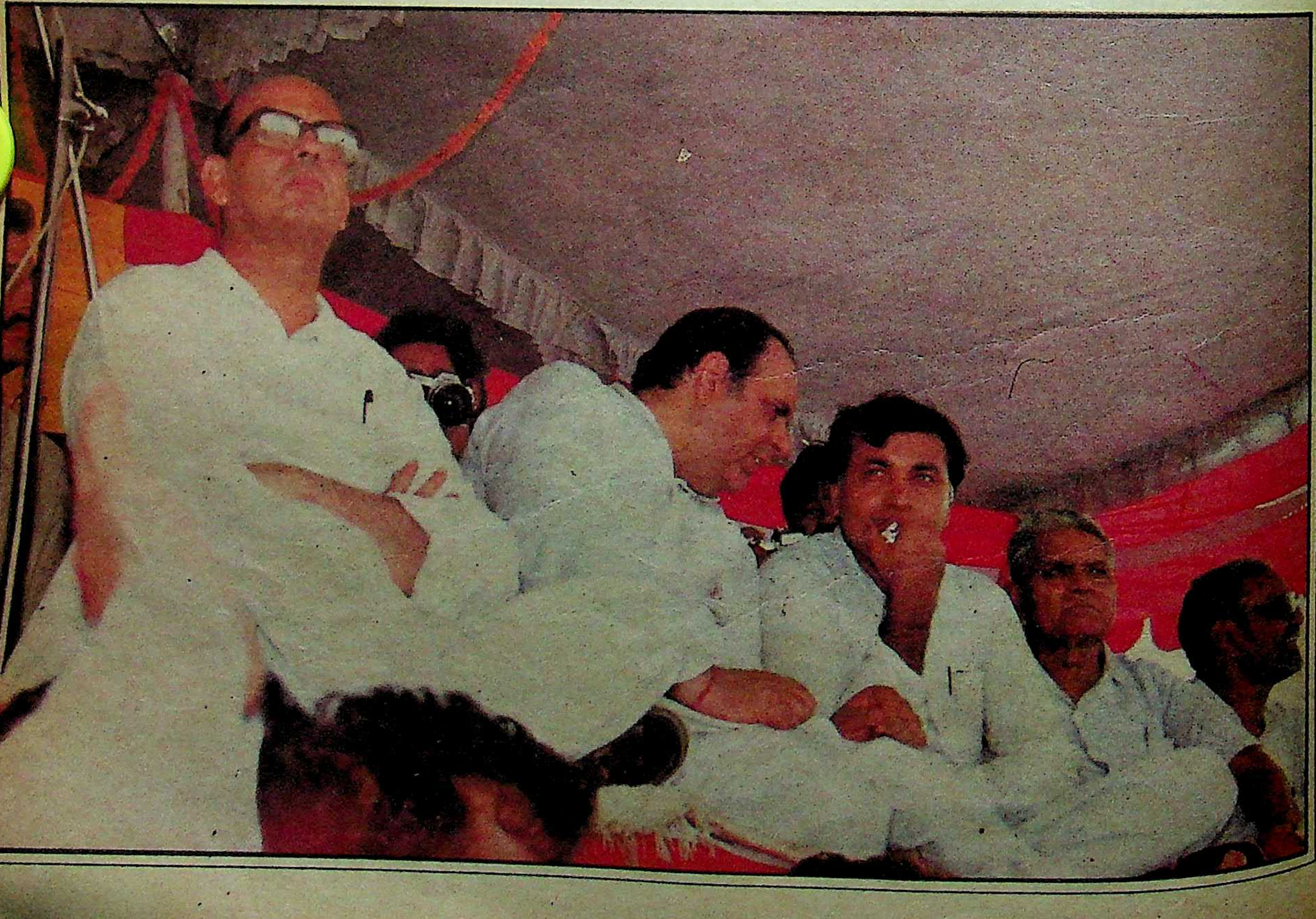
विद्रोही तिकड़ी : वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ

जनप्रवाह के बीच: मुजफ्फरनगर में अरुण नेहरू, वी०पी० सिंह

छाया: इमेज क्रिएटर

जानता है कि छुट्टी के दिनों में इन स्थानों पर अरुण नेहरू का पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं।

आशंका : अरुण नेहरू के खिलाफ अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। उन पर अब आरोप लगाया जा रहा है कि जब वह आतंरिक सुरक्षामंत्री थे, तो पिस्तौलों की खरीदी में गोलमाल हुआ था। विन चड्ढा कभी अरुण नेहरू से मिले थे—इस खबर का प्रकाशन भी नेहरू को बदनाम करने के लिए बेमन से उठाया गया एक कदम था। वस्तुस्थिति यह है कि नेहरू परिवार का एक सदस्य होने के नाते सांसद बनने के बाद से वह राजीव गांधी की हर योजना और गतिविधि में बड़े करीब से शामिल रहे हैं और यही भय है कि जाने कब वह कौन से रहस्य उगलने लगें। यही वजह थी कि राजीव गांधी के झंडाबरदार अरुण नेहरू की खुलकर निंदा करने लगे। गत मास ऐसी चर्चाएं थीं कि अमिताभ बच्चन की शह पर 'हिंदुजा बंधु' ऐसे दस्तावेज ले आये हैं, जिनसे अरुण नेहरू पर अभियोग चलाया जा सकता है। गत २५ जून को 'हिंदुजा बंधुओं' के सबसे बड़े भाई राजीव गांधी से मिले भी थे, लेकिन एक ओर जहां राजीव गांधी और उनके नये मित्र गहरे दलदल में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अरुण नेहरू तूफानी गति से जनसभाओं में अधिकाधिक शामिल होने लगे हैं और लोगों को अब उनके अतीत में दिलचस्पी नहीं रही। अरुण नेहरू और उनके आदमियों ने बड़ी कुशलता से स्वयं को वी०पी० सिंह के सिपहसालार के रूप में स्थापित कर लिया और इस समय आम जनता में वी०पी० सिंह की लोकप्रियता दिनोंदिन प्रबल होती जा रही है।इस समय असंतुष्ट नेता जो चालें चल रहे हैं, उनके सूत्रधार अरुण नेहरू हैं जो विरोधियों को ठिकाने लगा देने में माहिर माने जाते हैं।वह अरुण नेहरू ही थे, जिन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि हर सांसद और सत्ताकेंद्र में रहनेवाले हर व्यक्ति को स्वयमेव प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह अधिकार दे देना चाहिए कि वह चाहें तो उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खातों के संबंध में स्विस बैंक से

> **अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सिंह जनआंदोलन के नेता हैं और नेहरू मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए आंदोलन के लिए राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को एक जुट कर रहे हैं। वास्तव में अब दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य बन चुके हैं।**

जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके जवाब में तत्काल राजीव गांधी के खेमे से स्वयं अरुण नेहरू पर स्विट्जरलैण्ड में संपत्ति बनाने के वैसे ही आरोप लगाये जाने लगे, जैसे कि अजिताभ बच्चन पर लग रहे हैं।

मंत्रणा : हाल में अरुण-नेहरू के फार्म हाउस पर वी०पी० सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, रामधन, सतपाल मलिक और अन्य असंतुष्ट नेता परिवार सहित मिले थे। इस बैठक में आर्थिक अपराधियों के खिलाफ अभियान को उग्र बनाये रखने की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श हुआ। वास्तव में यह बैठक वी०पी० सिंह को लोकनायक के रूप में स्थापित करने और १६८६ के अंत तक, तब तक राजीव सरकार के विरुद्ध अभियान जारी रखने की योजना बनाने के लिए हुई थी, जब तक कि वह अपनी ही मूर्खताओं के भार से ढह नहीं जाती। इस घात-प्रतिघात के खेल के अरुण नेहरू शातिर खिलाड़ी हैं। अरुण नेहरू को सबसे बड़ी सहूलियत यही है कि वह राजीव गांधी की मानसिकता और मिजाज को किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते हैं। उन्हें श्रीमती गांधी से राजनीतिक सबक सीखने का भी लाभ मिला है।

माना तो यह जाता है कि अरुण नेहरू को श्रीमती गांधी राजनीति में लायी थीं, जबकि असलियत दूसरी है। जब अरुण नेहरू १६८० में संजय गांधी द्वारा टेलीफोन से बुलाये जाने पर दिल्ली आये थे, तो श्रीमती गांधी ने १२ विलिंग्डन क्रीसेंट के अपने निवास में अरुण नेहरू से एक घंटे तक बातचीत की थी। वह नहीं चाहती थीं कि अरुण नेहरू जानसन-निकलसन की ऊंची नौकरी छोड़कर

अरुण नेहरू मई, १६८६ में श्रीनगर में हुए हृदयाघात के बाद से राजनीति के अंधेरे में हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की परंपरा के अनुसार ही जोड़तोड़ की राजनीति में संलग्न होना भी नये नेहरू की नियति बन गयी है। यह नया नेहरू उस नेहरू से कहीं अधिक खतरनाक है जो कंप्यूटर के पीछे बैठा करता था और जो नौकरशाह वृत्ति के कांग्रेस-महासचिवों पर कांग्रेस कार्यालय २४, अकबर रोड में बरस पड़ता था।

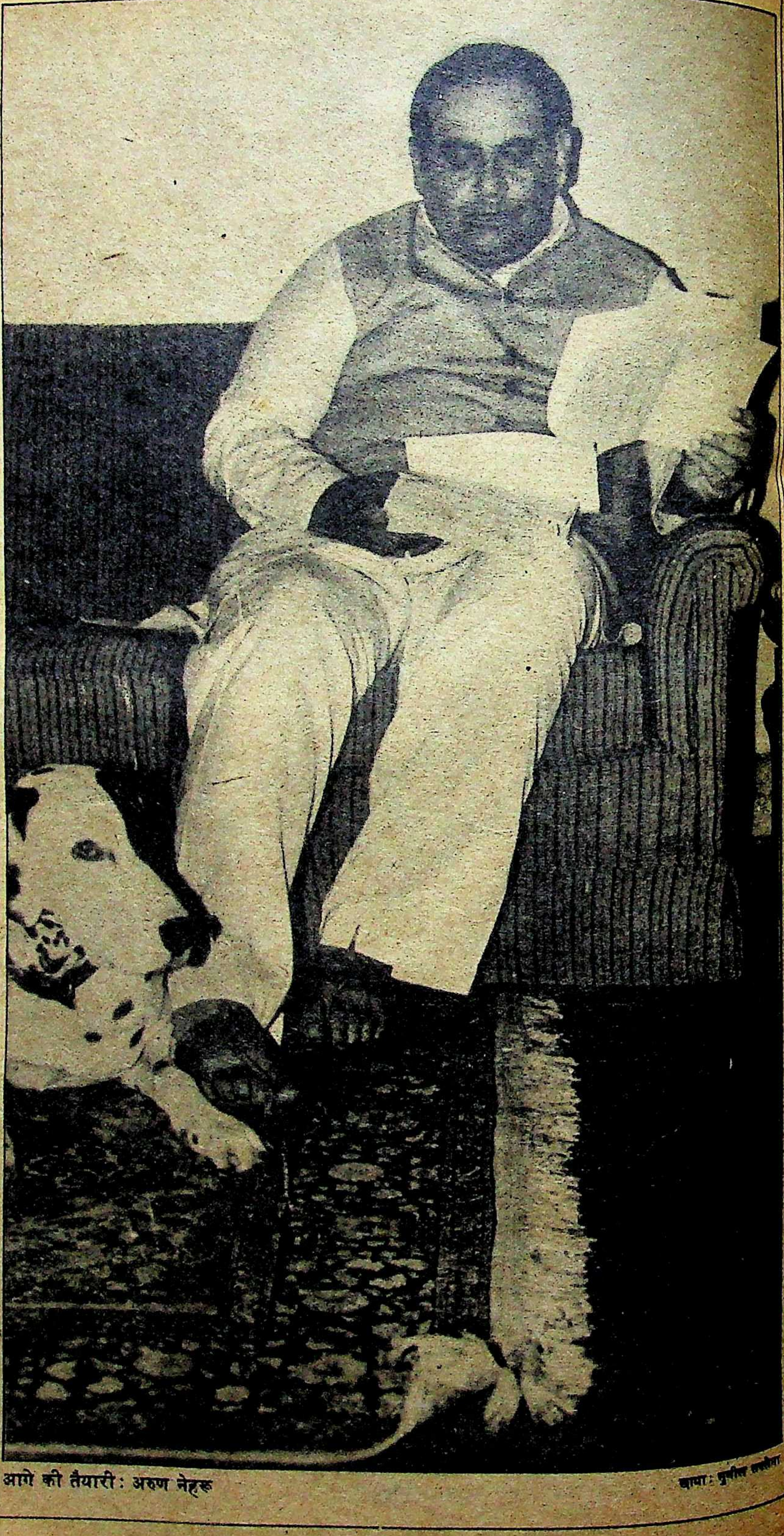
आगे की तैयारी : अरुण नेहरू

छाया : [illegible]

राजनीति में आयें। उन्होंने अरुण नेहरू को राजनीति में आनेवाले खतरों से आगाह कर दिया था। लेकिन संजय गांधी चाहते थे कि अरुण नेहरू राजनीति में आयें। श्रीमती गांधी ने मेडक संसदीय सीट के एवज में रायबरेली की सीट छोड़ दी थी। रायबरेली की जनता यह समझने लगी थी कि १६७७ की हार से क्षुब्ध होकर श्रीमती गांधी ने अपना चुनाव क्षेत्र बदल लिया है। रायबरेली से भावनात्मक लगाव होने के कारण स्वयं श्रीमती गांधी चाहती थीं कि उनके ही परिवार का कोई सदस्य इस क्षेत्र से उपचुनाव लड़े। तब बी०के० नेहरू का नाम सामाने आया था, लेकिन चूंकि बी०के० नेहरू श्रीमती गांधी की राजनीतिक शैली और नीतियों के आलोचक थे, इसी कारण संजय गांधी नहीं चाहते थे कि वह रायबरेली से चुनाव लड़ें। संजय के विरोध और अरुण नेहरू के राजनीति में आने के निश्चय को भांपकर श्रीमती गांधी ने स्वयं उत्साहपूर्वक उनके चुनाव-प्रचार की रूप रेखा तैयार की। यह चुनाव प्रचार पूरी तरह एक पारिवारिक मामला था। अरुण नेहरू की मां सूरज नेहरू चचेरा भाई संजय गांधी और स्वयं श्रीमती गांधी चुनाव-प्रचार में जुटी थीं। कमलापति त्रिपाठी और वी०पी० सिंह जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ही ऐसे अपवाद थे, जिन्होंने अरुण नेहरू के चुनाव-प्रचार में भाग लिया था। उस समय श्रीमती गांधी ने अरुण नेहरू को पहला राजनीतिक सबक सिखाया था, "संघर्ष करो और कठिन संघर्ष करते रहे।" यही वह सबक है, जिसे अरुण नेहरू ने आज बड़ी संजीदगी से याद रखा हुआ है। इसी दिलेरी से वह राजीव गांधी के सिपहसालारों—रायों और तिवारियों—से संघर्ष करने के लिए 'मलिकों और खानों' की बैठक आयोजित करते हैं।

हाल ही राज्यसभा में सतपाल मलिक ने कांग्रेस-इ सांसद होते हुए भी बोफोर्स-सौदे पर बोलने की जिद करके सरकार को परेशानी में डाल दिया था। सदन में कांग्रेस-इ के सांसदों ने बावेला मचाया और सतपाल मलिक को बोलने नहीं दिया गया। बताया जाता है कि वस्तुतः यह अरुण नेहरू की एक चाल थी, जिससे वह सरकार के असली इरादों का पर्दाफाश करना चाहते थे। अरुण नेहरू के एक पुराने साथी का कहना है, "नेहरू मुस्कराते हुए जहरीला कटाक्ष कर सकते हैं।" अपनी इसी कुशलता से वह छात्रों और ग्रामीण युवकों को प्रभावित करते हैं। राजीव गांधी भले ही सत्ता में हों, लेकिन अरुण नेहरू के घर आनेवाले युवकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अब अरुण नेहरू, वी०पी० सिंह के साथ जनसभाओं में भाग ले रहे हैं, वह राजीव गांधी के नेतृत्व को चुनौती देनेवालों के साथ आम जनता से संपर्क कर रहे हैं। अचानक सारे समीकरण बदल गये। एक ममेरा भाई नैतिकतावादियों की ओर चला गया और दूसरा ममेराभाई राजीव ऐसे लोगों के बीच अकेला नजर आने लगा जो लोभी और सत्ता के भूखे माने जाते हैं।

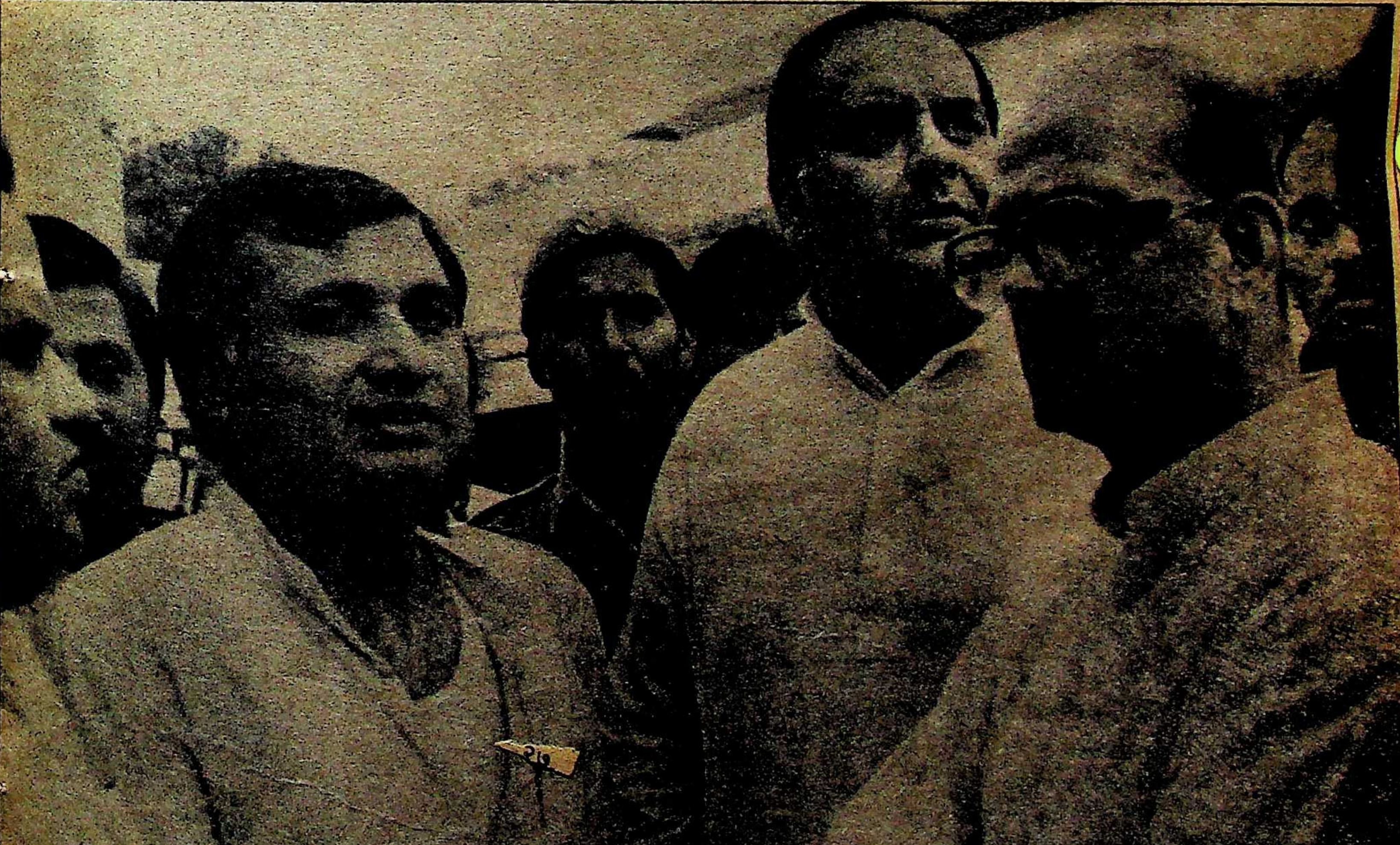

लड़ने पर आमादा: आरिफ, अरुण नेहरू, वी०पी० सिंह

छाया : कमल एंड-नारंग

अभी पिछले दिनों आरिफ मोहम्मद खान ने वी०पी० सिंह के जन्म दिन के बहाने एक चाय पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में अरुण नेहरू एक दर्जन से अधिक पत्रकारों के साथ जब तक पार्टी चली, तब तक खुलकर हास-परिहास करते रहे। जबकि डेढ़ वर्ष पूर्व हालत यह थी कि इन्हीं संवाददाताओं को अरुण नेहरू से पांच मिनट तक बातचीत करने का अवसर देने से इनकार कर दिया जाता था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अरुण नेहरू के तौर-तरीकों में अद्भुत बदलाव आया है और इसका समाचार माध्यमों पर भी अपेक्षित प्रभाव पड़ा। अचानक अरुण नेहरू पत्रिकाओं के कवर पर छा गये और जो लेखक उनके आलोचक थे, अब वे भी उन पर निरंकुश और रूखा होने का आरोप नहीं लगाते। उक्त चाय पार्टी में पत्रकारों से हुई २ घंटे की लंबी गपशप का जिक्र करते हुए एक वरिष्ठ संवाददाता का कहना था, "यह उनके कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन था।" अरुण नेहरू के इसी कौशल से संचालित परदे के पीछे की गतिविधियां राजीव गांधी के सहायकों के लिए समस्याएं खड़ी कर रही हैं।

भावी रणनीति : आनेवाले दिनों में नेहरू क्या चालें चलेंगे, उनका खुलासा धीरे-धीरे हो रहा है। पार्टी से निष्कासन के बाद अरुण नेहरू ने राजीव गांधी और उनके सहायकों की गतिविधियों पर बारीक नजर रखी है। ऐसा लगता है कि वह अपने वफादारों के जरिये राजीव गांधी और उनके आदमियों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर प्रहार करने की तैयारी कर चुके हैं, जबकि उनके विरोधी इस भय से सहमे-सहमे रहेंगे कि यदि स्वयं अरुण नेहरू ने खुलकर बोलने का फैसला किया, तो वह जाने क्या बोल जायें। राजीव खेमे को उम्मीद है कि नेहरू कभी भी वी०पी० सिंह के नेतृत्व से तालमेल नहीं बैठा पायेंगे और स्वयं सिंह कभी भी नेहरू की पूंजीवादी पृष्ठभूमि को स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे के कठिन क्षणों में एक साथ खड़े नजर आते हैं। मंत्रिमंडल से नेहरू के निष्कासन के तत्काल बाद वी०पी० सिंह उनके घर पहुंचे और जिस दिन अरुण नेहरू को पार्टी से निकाला गया, उस दिन वी०पी० सिंह हरिद्वार दौरे पर थे, उसी शाम को उन्होंने राजीव गांधी को एक कठोर पत्र लिखा और नेहरू से फोन पर बातें कीं। उसी पत्र की पंक्तियों को उदधृत करते हुए नेहरू प्रशंसाभाव से कहते हैं, "उन्होंने (सिंह) कहा है कि गोडसे को भी सफाई देने का मौका दिया गया था। अब वह (सिंह) नेता के लहजे में साफ-साफ बातें करने लगे हैं।" यह सिंह के बारे में अरुण नेहरू के विचारों का पक्का सबूत है।

अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सिंह जन-आंदोलन के नेता हैं और नेहरू मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए आंदोलन के लिए राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। वास्तव में अब दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य बन चुके हैं। सिंह को ऐसे संगठनकर्ता की आवश्यकता है जो साधन संपन्न, स्पष्ट दिमागवाला और विश्वसनीय

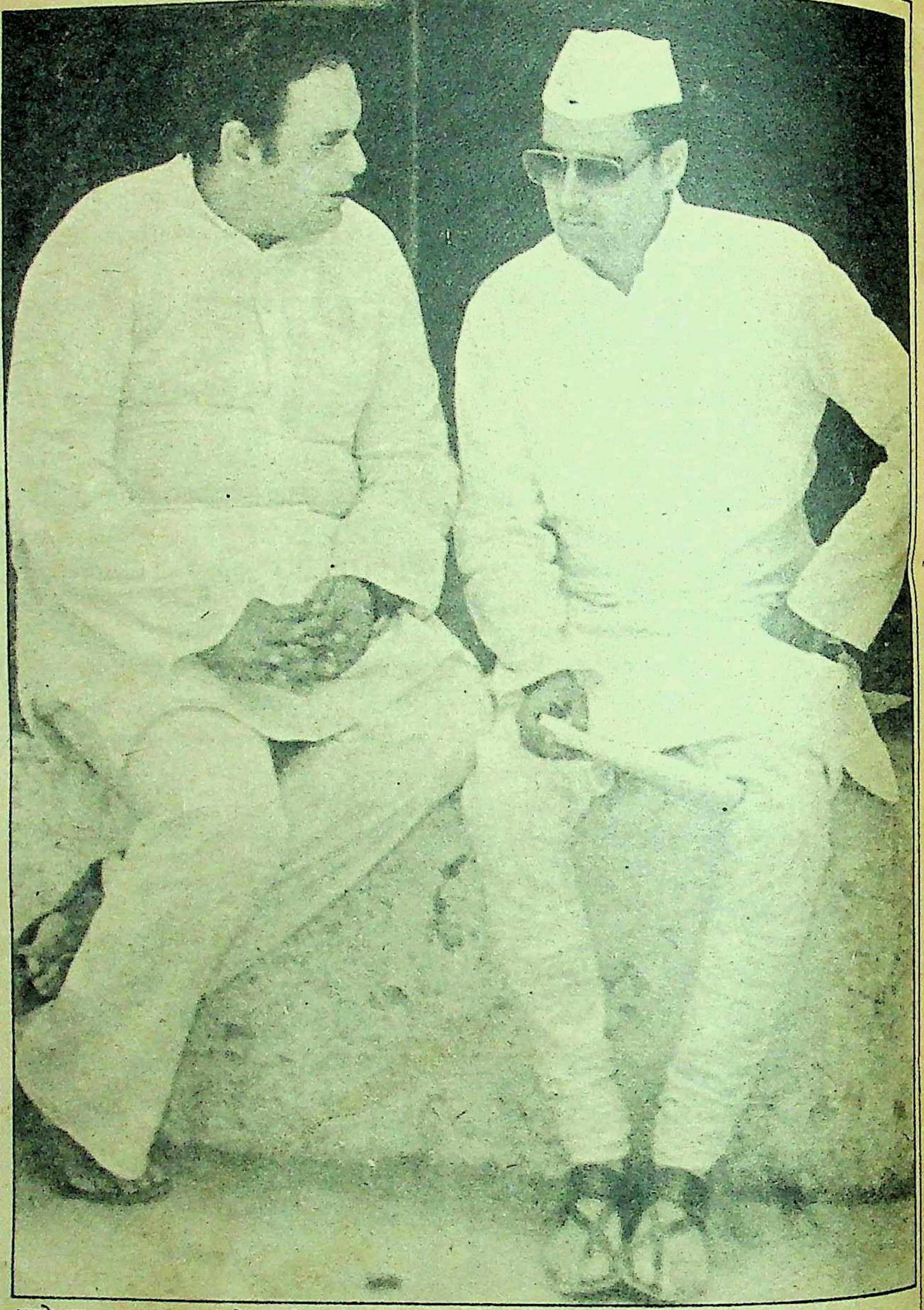

पहले साथ-साथ, अब आमने-सामने : अरुण नेहरू और राजीव गांधी

१७ महीनों से वीरानी में रहनेवाले अरुण नेहरू ने संजय गांधी के समान अपनी राजनीतिक कुशलता को धारदार बना लिया है। राजीव गांधी का यह ममेरा भाई एक समय उनका अंतरंग सहयोगी था, लेकिन आज वह कट्टर शत्रु बन चुका है और अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए कृतसंकल्प है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अब दोनों के बीच शांति और समझौते की सब संभावनाएं समाप्त हो गयी हैं।

हो। नेहरू को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आम जनता में लोकप्रिय हो और जो सत्ता-ग्रहण करने और उसका संचालन करने में समर्थ हो। इसका परिणाम यह हुआ है कि दोनों ने आपस में अपने मतभेदों को दूर कर लिया है। व्यावसायिक घरानों के संबंध में सिंह के, तो आम आदमी के संबंध में अरुण नेहरू के नजरिये में बदलाव आया है। खादी के कपड़ों में नेहरू अब आम आदमी से हिल मिलकर बातें करते हैं। राजघाट पर वह पसीने से तरबतर राजगीरों से बड़ी आत्मीयता से बातें कर रहे थे। भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे वह वी०पी० शुक्ला और आरिफ मोहम्मद खान से कहीं अधिक सहज नजर आ रहे थे। इसी कारण यह माना जा रहा है कि नेहरू और सिंह का जनाधार बढ़ रहा है और वे इसके प्रति सचेत हैं।

वफादारों की खुशफहमी: राजीव-समर्थकों को उम्मीद है कि नेहरू के साथ होने से वी०पी० सिंह की इस छवि को धक्का लगेगा कि वह पूंजीपतियों से घृणा करते हैं और उनसे धन लेने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन राजीव खेमे के लोगों की यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। स्वयं अरुण नेहरू ने १९८४ के चुनावों में धन-संग्रह के कार्य से स्वयं को कुशलतापूर्वक दूर रखा था। वास्तव में उन्होंने कूपन पद्धति प्रचलित की थी। जो भी व्यक्ति कांग्रेस-इ के चुनाव कोष में धन देना चाहता था, उसे २४-अकबर रोड से उतनी कीमत का कूपन खरीदना होता था। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि रक्षा-सौदों से अरुण नेहरू का कोई संबंध नहीं रहा है। अरुण नेहरू ने कभी भी इन्कार नहीं किया कि वह सूरी और थापर जैसे पूंजीपतियों से निकट से परिचित हैं। वीर बहादुर सिंह जैसे लोगों द्वारा उनसे अलग हो जाने के कारण भी अरुण नेहरू की छवि उजली हुई है और लोगों की इस धारणा में बदलाव आया है कि अरुण नेहरू ने भ्रष्ट लोगों को चुना और उनका समर्थन किया।

आनेवाले दिनों में नेहरू क्या चालें चलेंगे, उनका खुलासा धीरे-धीरे हो रहा है। पार्टी से निष्कासन के बाद अरुण नेहरू ने राजीव गांधी और उनके सहायकों की गतिविधियों पर बारीक नजर रखी है। ऐसा लगता है कि वह अपने वफादारों के जरिये राजीव गांधी और उनके आदमियों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर प्रहार करने की तैयारी कर चुके हैं।

वी०पी० हमारी टीम के नेता हैं: अरुण नेहरू

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

अरुण नेहरू पर पंजाब और कश्मीर में राजनीतिक लापरवाहियां बरतने का आरोप भी ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि नेहरू के हट जाने के बाद भी इन प्रदेशों में हालात और गंभीर होते चले गये। अब नेहरू कह सकते हैं कि उन्होंने तो राजीव गांधी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से लिये गये निर्णयों को ही सरअंजाम दिया था (देखिए साक्षात्कार)। सत्ता में कठोरता और अक्खड़ता के प्रतीक माने जाने वाले नेहरू को अब संघर्ष पुरुष माना जाने लगा है। इससे ४०० सांसदों द्वारा रक्षित राजीव गांधी का तख्ता पलटने के इच्छुक वी०पी० सिंह एवं अन्य लोगों को एक प्रबल संबल मिल गया है।

अरुण नेहरू ने १९८४ के संसदीय और १९८५ के विधानसभा चुनावों के लिए जिन लोगों का चयन किया था, आज वे उनके साथ नहीं हैं। अरुण नेहरू ने कभी ऐसा कहा या नहीं, लेकिन उन पर यह कहने का आरोप अवश्य लगा कि 'असली नेहरू तो वह स्वयं हैं'। बहरहाल, जिस प्रकार वी०पी० सिंह की लहर चल रही है, उसे देखते हुए यह आरोप एक सचाई भी बन सकती है। स्वयं अरुण नेहरू का कहना है, "मैं यह नाम (नेहरू) लेकर जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने इसकी इच्छा नहीं की थी।"

—दिल्ली ब्यूरो

साक्षात्कार/अरुण नेहरू

दुबारा से जनादेश लेने के सिवा कोई चारा नहीं

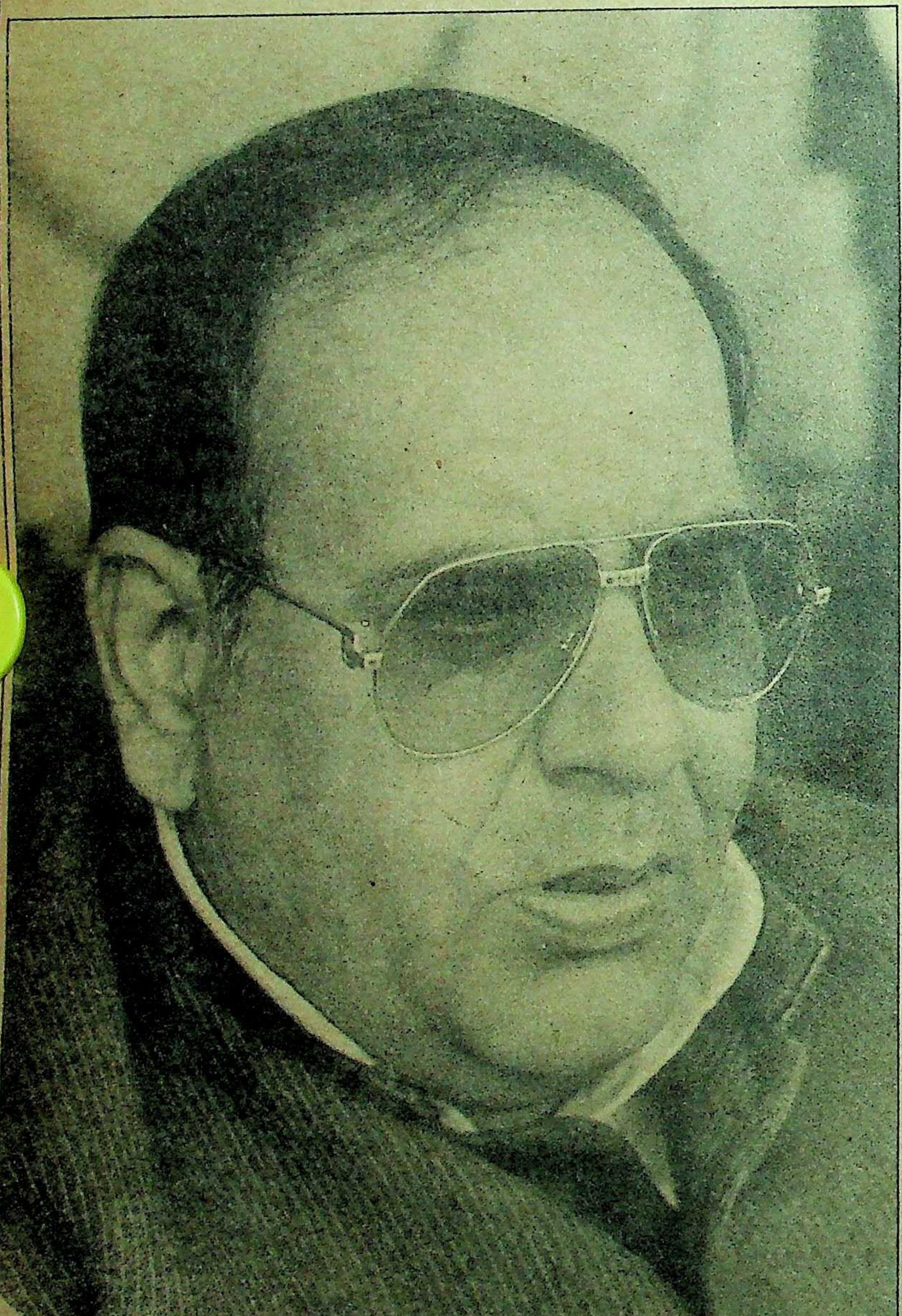

माया: विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ आपके समीकरण का मूल उद्देश्य क्या कांग्रेस-इ का विरोध करना है?

नेहरू: समीकरण शब्द ठीक नहीं है। हमारी एक टीम है और विश्वनाथ प्रताप सिंह उस टीम के नेता हैं।

माया: क्या यह सही है कि इस समय आपकी जरूरत है, इसलिए आपसे उनकी दोस्ती है?

नेहरू: मेरे दोस्त, दोस्त होते हैं। लोगों से मेरा रिश्ता स्थितियां या रुतबा बदल जाने से नहीं बदलता।

माया: वी०पी० सिंह के प्रति उ०प्र० सरकार के रवैये के बारे में आप क्या महसूस करते हैं?

नेहरू: मेरे लिहाज से अभद्र रहा है। आप उ०प्र० के लोगों पर धारा १४४ नहीं लाद सकते। लोकतंत्र का मूल तत्व मतभेद है। भारत जैसे विशाल देश को आप क्षुद्र तरीके से नहीं चला सकते।

माया: जो व्यक्ति नेतृत्व और संगठन के हितों के खिलाफ काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति आप कांग्रेस-इ के नेतृत्व से उदारता की अपेक्षा कैसे करते हैं?

नेहरू: किसी भी व्यक्ति के चरित्र का पता उस समय लगता है, जब वह दबाव में होता है। किसी नेता का क्षुद्र होना, उसके लिए फायदेमंद नहीं है। हां, आपने जो कहा है—कांग्रेस-इ के हित के खिलाफ क्या है? बच्चन-बंधुओं की स्विट्जरलैंड स्थित संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करना, बोफोर्स सौदों में संलग्न नामों या अन्य रक्षा सौदों में देश के बाहर अवैध तरीके से जाने वाले धन की छानबीन करना, उसको उजागर करना आदि कोई भी कार्य क्या पार्टी या नेतृत्व के हितों के खिलाफ है?

माया: ऐसा लगता है कि अस्थिर करने की साजिश को लेकर कांग्रेस-इ का नेतृत्व और सत्ता के इर्द-गिर्द के लोग आतंकित हैं।

नेहरू: मेरी राय में अस्थिरता और सी०आई०ए० की बातें बिलकुल बकवास हैं। जब आप खुद अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, तो दूसरों पर दोष क्यों मढ़ते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल और हरियाणा के चुनावों में हार से सी०आई०ए० का क्या लेना-देना है?

माया: क्या आप सोचते हैं कि सौदों की जांच के लिए जो समितियां नियुक्त हुई हैं, उनसे कोई फायदा होगा?

नेहरू: यदि मामला आर्थिक सौदों का है, तो इसका कोई आम समाधान नहीं है। हर मामले को अलग-अलग उसके गुणावगुण के हिसाब से देखना होगा।

माया: १९८४ के चुनाव में आप प्रमुख व्यक्ति थे, जब राजीव गांधी भारी बहुमत से जीते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लगातार छह राज्यों के चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा?

नेहरू: १९८४ के चुनावों में जीत, इंदिराजी की जीत थी। हम उनकी शहादत के कारण जीते। मैं समझता हूं, जीत और हार तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पांच सालों के कार्यकाल में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात तो हार के कारणों का पता लगाना और उनको दूर करने के उपाय करना है। लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। एक व्यक्ति के लिए संगठन को उपेक्षित बनाया जा रहा है। यह बात व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए खराब है।

माया: प० बंगाल, केरल और हरियाणा की हार के लिए कांग्रेस-इ स्थानीय कारणों को जिम्मेवार मान रही है।

नेहरू: मैं तहेदिल से उम्मीद करता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझेगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो हम शुरू होने से पहले ही उस समय हार गये थे, जब श्री अर्जुन सिंह ने गोरखालैंड पर पार्टी का मत व्यक्त किया था। केरल में सांप्रदायिक परिस्थितियों के कारण और हरियाणा में पंजाब समझौते को पूरी तरह निरस्त कर दिये जाने और नेतृत्व में जनता के अविश्वास की बदौलत हार हुई। इसके लिए स्थानीय संगठन को दोषी बताना घाव पर नमक छिड़कना है।

माया: क्या आप यह मानते हैं कि इस समय कांग्रेस-इ संगठन का पुनर्गठन आवश्यक है?

नेहरू: इसका आश्वासन तो स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष काफी समय से दे रहे हैं।

माया: हाल में आप लगभग तीन सप्ताह तक भारत से बाहर रहे हैं। यह कहा जाता है कि आप स्वीडन, स्विट्जरलैंड और इटली गये थे।

नेहरू: (ठहाका)...अफसोस कि मैं इन देशों में नहीं गया। मैं इंग्लैण्ड अवश्य गया था और उसके बाद भूटान नरेश के अतिथि के रूप में भूटान गया था।

माया: आम तौर पर यह माना जाता है कि आप सांसदों और मंत्रियों के निरंतर संपर्क में हैं।

नेहरू: जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त हैं और वे बदलते नहीं हैं।

माया: आरिफ मोहम्मद के बयानों के पीछे आपका इशारा माना जाता है। यह कहा जाता है कि बयानों का निशाना जानबूझकर प्रधानमंत्री को बनाया जा रहा है।

मेरी राय में अस्थिरता और सी०आई०ए० की बातें बिलकुल बकवास हैं। जब आप खुद अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, तो दूसरों पर दोष क्यों मढ़ते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल और हरियाणा के चुनावों में हार से सी०आई०ए० का क्या लेना-देना है?

नेहरू: हम सबकी तरह आरिफ के अपने विचार हैं। हम दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको बयान देने के लिए मेरी राय की आवश्यकता है।

माया: उ०प्र० के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को आपका कृपापात्र माना जाता है।

नेहरू: (हंसकर) हरेक मेरा प्रियपात्र प्रतीत होता है। यह भी कहा जाता है कि मैंने ही प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था।

माया: यह माना जाता है वह (मुख्यमंत्री) आपके काफी करीब रहे हैं।

नेहरू: यह बात आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते?

माया: ऐसी अफवाहें थीं कि क्योंकि आप के साथ नेहरू शब्द लगा है, इसलिए आप सत्तारूढ़ लोगों के लिए एक खतरा थे?

नेहरू: यह बड़ी रोचक बात है। इस तरह की अटकलबाजियां रही हैं। बहरहाल, किसी की सुविधा के लिए मैं अपना नाम नहीं बदल सकता।

माया: भ्रष्टाचार, बोफोर्स, पनडुब्बी और खाद आदि के घोटालों के कारण कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा रसातल में चली गयी है।

नेहरू: यह बिलकुल साफ है और मामला और भी खराब हो रहा है, क्योंकि कार्यवाही सही रास्ते पर नहीं हो रही।

माया: आपकी दृष्टि में इन मामलों में कौन लिप्त हो सकता है?

नेहरू: मैं नहीं जानता। भारत के लोग चाहते हैं कि नाम सामने आयें। जनता को तकनीकी पेंचों से कुछ लेना-देना नहीं।

माया: क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस पर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तत्व हावी हो गये हैं?

नेहरू: दायें और बायें की बातें मुझे बड़ी अजीब लगती हैं। एक बार श्रीमती गांधी से पूछा था कि आपका झुकाव बायीं तरफ है या दायीं तरफ? उनका उत्तर था कि हम सीधे खड़े हैं। हमको अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम को अपने गुणों के लिए किसी व्यक्ति से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

माया: इस समय हम संसार की आंखों में हंसी के पात्र बने हुए हैं। भारत एक महान सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा का देश माना जाता रहा है, लेकिन अब रिश्वतखोरों का देश माना जाने लगा है।

नेहरू: यह सब बिलकुल बकवास है। ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुझे भारतीय मनीषा पर पूर्ण विश्वास है। किसी व्यक्ति-विशेष के कार्यों को देश के चरित्र का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमें बाहर की किसी विचारधारा की आवश्यकता है। हमारी अपनी परंपराएं हैं।

माया: क्या आप यह मानते हैं कि आप भारत को जानते हैं?

नेहरू: हां। सीखने की प्रक्रिया ताउम्र चलती रहती है। हर आदमी रोजाना कुछ सीखता है। किसी व्यक्ति की शक्ति इस तथ्य पर निर्भर है कि वह अपनी जिंदगी में लगातार कितना सीख रहा है। भारत एक विशाल देश है। जितना ज्यादा संभव है, उतना एक आदमी इसे जानने की कोशिश ही कर सकता है।

माया: बच्चन-बंधुओं के बारे में अनेक आरोप उछल रहे हैं। आपका मत क्या है?

नेहरू: दुनिया भर की बातें हो रही हैं। अनेक प्रकार के संदेह हो रहे हैं। बच्चन-बंधुओं के साक्षात्कारों ने मामला और बिगाड़ दिया है।

उनका यह कहना भारतीय भावनाओं पर चोट करता है कि भारत में सुरक्षा का अभाव है, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है।

माया: स्विट्जरलैंड में बच्चनों की संपत्ति के बारे में दस्तावेज छपे हैं। क्या उनके खिलाफ जांच की मांग उचित है?

नेहरू: हां—सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बच्चनों से करीबी संबंध रहे हैं, इसीलिए इस मामले से प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता भी जुड़ी है।

माया: आपको और वी०पी० सिंह को पार्टी के बाहर निकाल दिया, लेकिन बच्चन अब भी पार्टी के सदस्य हैं।

नेहरू: केवल पार्टी के सदस्य ही नहीं, बल्कि पंडितजी और नेहरू परिवार से जुड़े कई ट्रस्टों और संगठनों के सदस्य भी हैं? मैं कह चुका हूं कि जब तक इस मामले में वह बरी नहीं हो जाते, उन्हें इन सबसे इस्तीफा दे देना चाहिए।

माया: बोफोर्स से नामों को निकलवाने के लिए आपकी क्या योजना है?

नेहरू: इंतजार करिए और देखिए। यह केवल हमारी ही चिंता का विषय नहीं है। यह तो भारतीय जनता मांग कर रही है कि नामों का उद्घाटन होना चाहिए।

माया: वी०पी० सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह सी०आई०ए० से मिल कर देश को अस्थिर कर रहे हैं—आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

नेहरू: यह बिलकुल बकवास है।

माया: श्रीलंका समझौते के बारे में आपको क्या कहना है?

नेहरू: यह तो वक्त ही बतायेगा। पहले से नतीजे निकालना ठीक नहीं होगा।

माया: उस समय आपको कैसा लगा, जब आपको पार्टी से निष्कासित कर दिये जाने की सूचना मिली।

नेहरू: गहरे दुख का अहसास हुआ। मुझे अफसोस हुआ कि राजीव को ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि दोस्त भी दुश्मन बन गये हैं। विचारों में अंतर होने का मतलब विरोध नहीं है। बहरहाल अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं।

माया: जब राजीव गांधी श्रीलंका से लौटे, तो आपको हवाई अड्डे पर देख कर लोगों को आश्चर्य हुआ।

नेहरू: इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ऐसे मामले में कोई भी ओछेपन से काम नहीं लेता।

माया: आपको कश्मीर समझौते के खिलाफ और १९८३ में फारूख सरकार को गिराने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

नेहरू: मैं किसी भी समझौते के खिलाफ नहीं, लेकिन यह हमेशा महसूस करता रहा हूं कि कांग्रेस-इ के हित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। १९८३ में मेरे को जो जिम्मेदारी दी गयी थी, उसे मैंने पूरा किया था। मैं जानता हूं कि जानबूझकर झूठी बातें फैलायी जा रही हैं। १९८३ में जो कुछ भी हुआ, वह पार्टी और कैबिनेट का निर्णय था। ऐसे मुद्दे मामूली नहीं होते और कोई व्यक्ति विशेष इन पर निर्णय नहीं करता। यह तो वैसे ही नासमझी वाली बात हुई, जैसे कोई कहे कि श्रीलंका समझौता प्रधानमंत्री और नटवर सिंह ने किया है।

माया: एन०टी०आर० का तख्ता पलटने के लिए भी आपको ही जिम्मेदार माना जाता है।

नेहरू: आपके लिए यह रोचक जानकारी है कि जो भास्कर राव कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उनसे मैं न कभी मिला हूं और न मेरी उनसे कभी बातें हुई हैं। इस मामले में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं समझता हूं, जीत और हार तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पांच सालों के कार्यकाल में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात तो हार के कारणों का पता लगाना और उनको दूर करने के उपाय करना है। लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। एक व्यक्ति के लिए संगठन को उपेक्षित बनाया जा रहा है। यह बात व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए खराब है।

माया: इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को आपने ही चुना था?

नेहरू: जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरे बारे में तो यह भी कहा जाता है कि मैंने ही प्रधानमंत्री बनाया था।

माया: यह कहा जाता है कि जब वी०पी० सिंह उ०प्र० के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनसे आपके गंभीर मतभेद थे।

नेहरू: यह बात आप वी०पी० सिंह से क्यों नहीं पूछते? हमारे बेहद अच्छे संबंध थे। मुझे श्रीमती गांधी ने जो जिम्मेदारियां दे रखी थीं, मैं निबाहता था और विश्वनाथजी ने निस्संदेह बेहतर तरीके से राज्य को चलाया।

माया: क्या आप सोचते हैं कि वी०पी० सिंह ने उ०प्र० के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का काम किया था?

नेहरू: इसका जवाब देने के लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता। इतना जानता हूं कि वी०पी सिंह के मन में श्रीमती गांधी के प्रति अपार आदर रहा है। स्वयं श्रीमती गांधी भी उन्हें बेहद आदर देती थीं। मुझे याद है, १९८० के मेरे प्रथम चुनाव-प्रचार के दौरान यह तय हुआ था कि केवल परिवार के लोग ही चुनाव-प्रचार में भाग लेंगे। लेकिन श्रीमती गांधी ने दो लोगों को इस फैसले का अपवाद रखा था—एक कमलापति त्रिपाठी और दूसरे वी०पी० सिंह। उन्होंने इस बात को जरूरी माना था कि उनके और संजय के अतिरिक्त ये दोनों व्यक्ति रायबरेली का दौरा करें।

माया: क्या आप तब से राजीव गांधी के खास ढांचे के हिस्से रहे हैं, जब से वह राजनीति में आये थे।

नेहरू: हां भी और ना भी। मैं उनके व्यक्तिगत कार्यालय में विजय धर और अरुण सिंह की तरह नही रहा। राजनीतिक मामलों में हम साथ-साथ काम करते थे। मूल रूप में १९८१ से ८४ के बीच हम पार्टी से संबंधित काम करते थे और प्रतिदिन श्रीमती गांधी से निर्देश लेते थे कि क्या करना है। कांग्रेस-इ के महामंत्री के रूप में मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री ने युवा कांग्रेस व सेवादल जैसे अग्रणी संगठनों को काफी बढ़ावा दिया।

माया: क्या आप मध्यावधि चुनाव की मांग कर रहे हैं?

नेहरू: सरकार और नेतृत्व की हालत जनता के सामने है। मैंने पहले भी कहा है कि सामान्य स्थितियों में मध्यावधि चुनाव आवश्यक नहीं होता। लेकिन वर्तमान हालात में अनेक संदेह उभर रहे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कोई लाभ नहीं प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि दुबारा से जनादेश लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। ■

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

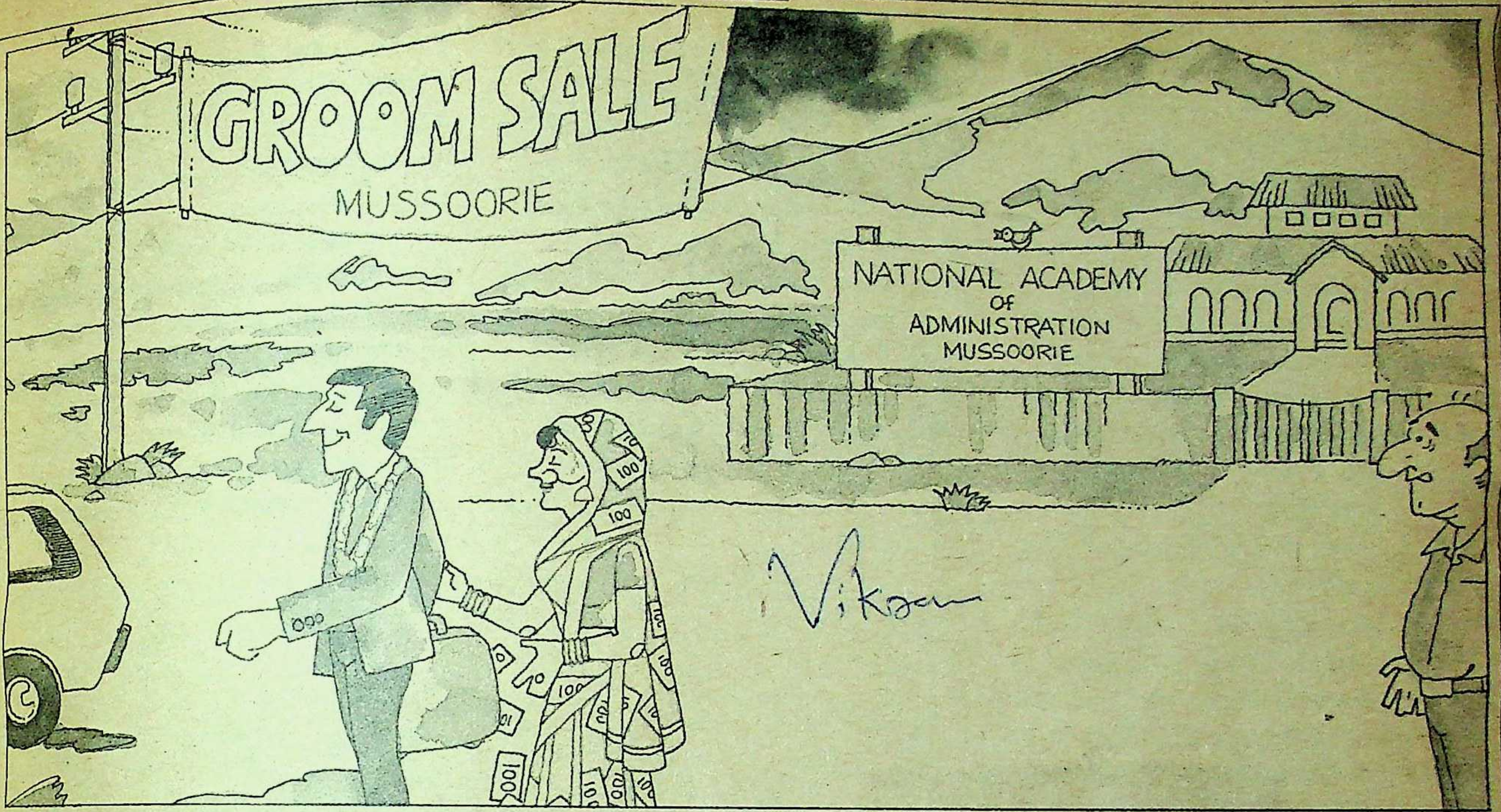
GROOM SALE
MUSSOORIE
NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION MUSSOORIE
100

महंगे दूल्हों का उत्पादन केंद्र

खरीदिए आई०ए०एस० दूल्हा तीस लाख में

अखबारों में नीलामी की कोई घोषणा नहीं छपी और न ही चीजों की कोई सार्वजनिक नुमाइश ही लगी, लेकिन मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण अकादमी के गेट पर जुलाई-अगस्त में आलम यह है कि सजे-धजे दंपती भीड़ लगाये हुए हैं। यह भीड़ उसी तरह की है, जिस तरह की लंदन में पुरातत्वीय सामानों की नीलामी के समय होती है। दोनों भीड़ों में बस एक फर्क है—खरीदे जानेवाले सामानों का। भव्य शास्त्री अकादमी में ये दंपती अपनी कन्याओं के लिए वर तलाशने, बल्कि सच कहा जाये, तो खरीदने आये हैं। वे एक आई०ए०एस० अफसर को अपना दामाद बनाने की कीमत १५ लाख रुपए तक देने को तैयार हैं, जो छह वर्षों में बड़ा साहब बन जायेगा। अकादमी के चारों तरफ सौदे हो रहे हैं। किसी भी 'साहब' के हां कहते ही भावी श्वसुर अपनी जेब से लाखों रुपए के नोट निकाल कर अपने भावी दामाद के सामने रख देता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने केंद्रीय गृहराज्यमंत्री पी० चिदंबरम को एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार एक आई०ए०एस० अधिकारी की कीमत पांच से बीस लाख रुपए तक दी जा रही है। कुछ खास योग्यतावाले लड़कों की कीमत तो ३० लाख रुपए तक लग चुकी है। रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि ज्यादातर प्रशिक्षणार्थी प्रशासनिक सेवा में नियुक्त होते ही शादी करते हैं और खुल्लम-खुल्ला दहेज लेते हैं। यह 'दहेजी सौदा' प्रशिक्षणार्थी या तो खुद कर लेते हैं या फिर अपने अभिभावकों की मंजूरी से करते हैं। इस्पात एवं खान मंत्रालय में सचिव और पूर्व में अकादमी के उप निदेशक (१९६३-६८) रह चुके आर०पी० खोसला का कहना है, "मैं जो कुछ सुन रहा हूं उससे ऐसा लगता है कि दहेज प्रथा अब व्यवस्था का एक अंग बन गयी है। हालात बहुत बदल गये हैं। पहले ध्यान दिया जाता था कि वर-वधू का जोड़ा मिलना चाहिए, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। जब मैं पूर्वनिदेशक था तब विवाह योग्य आई०ए०एस० प्रशिक्षणार्थियों की सूची मांगने वाले पत्र शायद ही आये हों। दंपती भी अकादमी के चक्कर नहीं लगाते थे।" रिपोर्ट के अनुसार दो तिहाई न सही एक तिहाई प्रशिक्षणार्थी तो दहेज की मांग अवश्य करते हैं।

ऐसी बात नहीं है कि सभी आई०ए०एस० दहेज लोलुप होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे—खेल और कल्याण मंत्रालय में आंध्र प्रदेश कैडर के नौजवान आई०ए०एस० बी०वी०पी० राव। श्री राव ने कई विवाह प्रस्तावों को सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें भारी दहेज का लालच (कुछ प्रस्तावों में ३० लाख रुपए तक) दिया जा रहा था। श्री राव का कहना है कि नौकरी मिलते ही मेरे घर विवाह-प्रस्तावों की बाढ़ मी आ गयी। इन प्रस्तावों में सबसे पहले पैसों की बात की जाती थी। श्री राव पूछते हैं कि "यह शादी है या कोई व्यापारिक लेनदेन ?"

योगेंद्र नारायण यातायात मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उन्हें कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर झटका सा लगा। उनका कहना है कि १९६० में जब मैं अकादमी में था तब ऐसी घटनाएं अपवाद स्वरूप हुआ करती थीं। श्री नारायण के अनुसार उनके माथुर समुदाय में 'शादी की एक किताब' बनाकर रखी जाती है जिसमें संभावित दूल्हों की सूची होती है। हमारे समाज में दहेज पर कड़ा प्रतिबंध है। मगर अब लगातार नियमों को तोड़ा जा रहा है। कहीं-न-कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। अकादमी के अधिकारी इसके लिए चिंतित हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपनी इस चिंता का इजहार भी करते हैं। यदि इस संबंध में अकादमी के बाहर से कोई कार्यवाही होती है, तो अकादमी के अधिकारी उसका स्वागत करेंगे।

महिला अफसरों की स्थिति : यदि आई०ए०एस० सेवाओं के कारण दहेज लेने की स्पर्धा बढ़ी है

तो प्रश्न उठता है कि महिला आई०ए०एस० अधिकारियों के साथ क्या हो रहा है ? ज्यादातर तो प्रशिक्षण के दौरान ही 'प्रेम विवाह' कर लेती हैं। योगेंद्र नारायण के अनुसार, "मगर जो अविवाहित ही अकादमी से प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं, उनसे कोई भी दहेज मांगने की हिम्मत नहीं करता।" एक महिला आई०ए०एस० ने हिंदुस्तान टाइम्स में वर हेतु विज्ञापन दिया। लेकिन विभिन्न कारणों से सुंदर होते हुए भी उसे मनपसंद पति नहीं मिल सका। तब महिला ने अखबारों में यह घोषणा कर दी कि वह एक आई०ए०एस० से शादी कर रही है। मगर उस आई०ए०एस० ने तुरंत ही इसका खंडन भी प्रकाशित करवा दिया। अंतत: उसके घरवालों को दहेज देकर ही अपनी आई०ए०एस० बिटिया के हाथ पीले करने पड़े।

आई०ए०एस० के अलावा अन्य सेवाओं में भी कम धमाचौकड़ी नहीं मची हुई है। जहां आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों की कीमत ५ से ३० लाख है वहीं आई०आर०एस० (भारतीय राजस्व सेवा) और आई०एफ०एस० (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी ५ से २० लाख रुपए में उपलब्ध हैं। दहेज की रकम काफी कुछ अधिकारी की जाति, क्षेत्र, घर की पृष्ठभूमि और वधू की शारीरिक कमियों पर निर्भर करती है। दक्षिण के बहुत से प्रांतों में कलेक्टर जैसे अधिकारियों को भगवान की तरह माना जाता है। लोग उन्हें अपना दामाद बनाने के लिए खासी रकम देने को तैयार रहते हैं। उत्तरी भारत में और खास तौर पर बिहार में तो हालात और भी खराब हैं। यहां तक कि खादीधारी मंत्री भी आई०ए०एस० दामाद खरीदने के लिए तैयार रहते हैं।

बिहार सबसे आगे : उत्तर भारत के वैवाहिक विज्ञापनों पर नजर डालने से पता चलता है कि अभिभावक गैरजाति में भी विवाह करने के इच्छुक हैं। इनकी संख्या भी बढ़ रही है। यह एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन इसके पीछे इन अभिभावकों का यह भी इरादा रहता है कि वे किसी भी कीमत पर आई०ए०एस० दामाद प्राप्त करें, भले ही वह किसी जाति का क्यों न हो।

कमेटी की रिपोर्ट का कहना है कि कम-से-कम तीन स्रोतों से पुष्ट जानकारी के अनुसार एक प्रमुख हिंदीभाषी राज्य के इंकाई मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक आई०ए०एस० प्रशिक्षणार्थी को पूरे एक करोड़ रुपए दहेज में देने का वायदा किया था। केरल का एक प्रकरण तो और भी अजीब है, जिसमें पुत्र के अचानक आई०ए०एस० में आ जाने के बाद माता-पिता ने भी पैंतरा बदल लिया। अधिक दहेज की मांग कर कन्या को कम सुंदर बताते हुए उन्होंने तयशुदा विवाह करने से इनकार कर दिया।

बिहार तो केरल से भी दस कदम आगे है। एक आई०पी०एस० अधिकारी ने जो शाहाबाद (बिहार) के एक जाने-माने परिवार से हैं और जिनका एक भाई आई०ए०एस० अधिकारी है, दो साल पहले अपने आई०ए०एस० पुत्र के लिए पांच लाख रुपए वसूले थे। इसी तरह उच्च न्यायालय के एक जज की पत्नी ने दलील दी थी कि उन्होंने अपने आई०ए०एस० पुत्र की पढ़ाई-लिखाई में ३ लाख रुपए खर्च किए थे, इसलिए वह इतना दहेज मांग रही है। यह १९७७ की बात है। मंहगाई बढ़ने के साथ-साथ यह मांग १० से १५ लाख पहुंच गयी है। इस सबके बावजूद ये आई०ए०एस० देश के प्रबुद्ध नागरिकों में गिने जाते हैं।

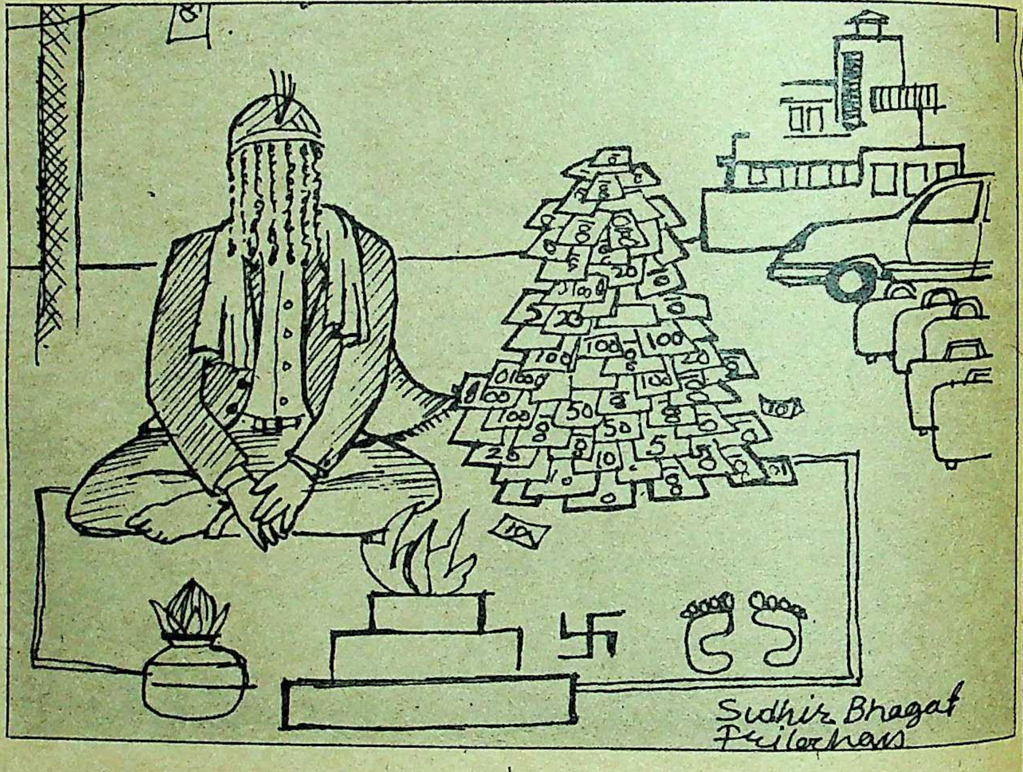

आई०ए०एस० दामाद की कीमतों के बढ़ने के पीछे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई समुदायों में व्याप्त कठोर जातीय संकीर्णता को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। एक जाति विशेष में ऐसे अच्छे वर कम मिलते हैं, लेकिन उनकी मांग ज्यादा रहती है। 'वस्तु कम और मांग अधिक' के आर्थिक सिद्धांत के आधार पर ऐसे वरों की कीमत तो बढ़ेगी ही। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आई०ए०एस० वर की कीमत उस समय और भी बढ़ जाती है जब वह अपने गृहनगर में तैनात हो। ऐसा माना जाता है कि तब अफसर दामाद से राजनीतिक और व्यावसायिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है इस कारण ऐसे वरों के दाम भी बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग इस दलील को नहीं मानते। स्वयं योगेंद्र नारायण का कहना है, वह श्वसुर वास्तव में मूर्ख है जो ऐसा सोचता है कि वह गृह प्रदेश में तैनात दामाद के जरिये आर्थिक एवं अन्य लाभ कमा सकता है। आखिरकार, हमें हर वर्ष विभाग को अपनी आर्थिक हैसियत की जानकारी देनी होती है।

पत्र सूचना कार्यालय (पी०आई०बी०) के प्रमुख सूचना अधिकारी राममोहन राय स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उन्होंने तय कर रखा है कि वह अपनी पुत्री का विवाह करते हुए वर के गुणों पर ही जोर देंगे, लेकिन केंद्र सरकार में सेवारत कुछ अधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपनी कन्याओं का आई०ए०एस० अफसरों से विवाह कराने के इच्छुक हों।

लेकिन कस्टम और एक्साइज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए अपनी बेटी के लिए आई०ए०एस० वर क्यों ढूंढू ? मेरी लड़की अपने डाक्टर पति के साथ खुश है और यही सब कुछ तो मैं चाहता था। लेकिन उन्हें यह अजीब लगता है कि उनके सुपरिंटेंडेंट और अन्य मातहत अधिकारी आई०ए०एस० दामाद खरीदने की हैसियत रखते हैं। यह अलग विषय है कि इतना धन उनके पास कहां से आया।

क्यों बढ़े आई०ए०एस० के भाव : एक दहेज लोलुप आई०ए०एस० प्रशिक्षणार्थी ने बताया, "यदि मैं आज दहेज में ५० लाख रुपए ले लेता हूं, तो फिर मुझे जीवन भर कुछ और लेने की जरूरत नहीं।" उसका यह कथन खेदजनक है।

भले ही उसने बड़ी ईमानदारी से यह बात कही है, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। यही वजह है जो लोग दहेज लेते हैं, वे (भले ही कम संख्या में हों) एक खतरनाक परंपरा डालते हैं। हो सकता है वे अपनी बहुओं को न जलायें, लेकिन वे लोगों की जेबों को जरूर जलाते हैं और हर स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देनेवाली नजीर बनाते हैं। जैसा कि आंध्र के दहेज विरोधी आई०ए०एस० अधिकारी बी०वी०पी० राव ने कहा है कि भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और प्रशासन में सबसे ऊपर आई०ए०एस० अधिकारी होते हैं, उनकी देखादेखी छोटे अधिकारी भी उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं।

आंध्र प्रदेश में पेट्रोडालर के आगमन से निचले तबके में भी आई०ए०एस० दामाद खरीदने की होड़ लग गयी है। उड़ीसा में तो हालात इससे भी दुखद और चौंकाने वाले हैं। समाज सेविका लतिका सरकार का कहना है कि ऐसी लड़कियों द्वारा आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है, जो सोचती हैं कि उनके पिता भारी दहेज नहीं दे सकेंगे। सुश्री सरकार को भुवनेश्वर के एक डाक्टर ने वह चट्टान भी दिखलाई जहां से लड़कियां छलांग लगाकर आत्महत्या करती हैं।

बिहार के एक सांसद और भूतपूर्व उद्योग मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में 'तिलक' की रकम में आश्चर्यजनक बढ़ोत्तरी हुई है। इस वजह से बहुतसी लड़कियों की शादी उनके गृह राज्य में नहीं हो पाती है।

प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष जस्टिस ए०एन० सेन का कहना है कि पुत्री के जन्म से ही सभी पिताओं की खुशी काफूर हो जाती है, इस चिंता में कि वह भारी दहेज की व्यवस्था कैसे करेंगे। जबकि उन माता-पिताओं के क्या कहने जिनके लड़के आई०ए०एस० हो जाते हैं यदि उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई-लिखाई के लिए कर्ज भी लिया हो तो वे दहेज लेकर उसे चुका सकते हैं।

दहेज लेना समाज-विरोधी कार्य है, लेकिन हाल में दूल्हों की कीमतें आखिर इतनी क्यों चढ़ गयी हैं? अधिकांश लोगों का कहना है कि यह बढ़ते काले धन और उपभोक्तावाद का नतीजा है। लेकिन लतिका सरकार प्रश्न करती हैं कि पश्चिमी देशों में तो यहां से ज्यादा उपभोक्तावाद है फिर वहां क्यों नहीं दहेज की मांग की जाती? कुछ सोचते हैं कि यह नवयुवकों की बढ़ती विलासप्रियता का नतीजा है।

प्रसिद्ध वकील गोविंद मुखोती के अनुसार ज्यादातर आई०ए०एस० धनी परिवारों से आते हैं। इच्छा-से-इच्छा का जन्म होता है, इसलिए उन्हें जब 'शादी की मंडी' में अच्छी कीमत मिलने लगती हैं तो वह उसकी मांग करने लगते हैं। युवक तो इसके लिए दोषी हैं ही लेकिन विवाह तय कराने में प्रमुख भूमिका निभानेवाली उनके पिता की पीढ़ी भी कम दोषी नहीं है। लतिका सरकार के अनुसार, "पुरानी पीढ़ी भले ही टी०वी० पसंद न करे लेकिन पुत्र इसकी मांग करे तो उसे एतराज भी नहीं होता।"

इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि दहेज की बुराई के लिए पारिवारिक ढांचा जिम्मेदार है। कन्या यहां बोझ समझी जाती हैं और उनका यथाशीघ्र किसी प्रकार विवाह कर देने की कोशिश की जाती है। केरल कांग्रेस में एक ईसाई मंत्री हैं, जिनकी अनेक कन्याएं हैं। वह हर वर्ष आई०ए०एस० प्रशिक्षणार्थियों में से अपनी कन्याओं के लिए योग्य वर की सूची बनाते हैं। भले ही उन्हें कितना दहेज देना पड़े, वह जल्दी-से-जल्दी अपनी कन्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं।

महिलाएं आगे आयें : अतः स्पष्ट है कि दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए महिलाओं को ही कमर कसनी होगी। दहेज मांगे जाने पर उन्हें शादी करने से इनकार कर देना चाहिए। दहेज के खिलाफ विद्रोह का बिगुल उन्हें ही बजाना होगा क्योंकि यह ऐसा मामला है जो उनके शोषण का कारण बनता है। लेकिन जहां तक प्रशासनिक सेवाओं के अफसरों में बढ़ती दहेज लोलुपता का सवाल है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। दहेज लेने का जरा भी संदेह होने पर यदि एक दो अफ़सरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई तो इस वर्ग में बढ़ती दहेज-प्रियता पर काफी कुछ काबू पाया जा सकता है।

गृह राज्यमंत्री पी० चिदंबरम को दी गयी रिपोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि अकादमी के निदेशक सभी आई०ए०एस० प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावकों को पत्र लिखकर सूचित करें कि यदि उनके पुत्र के विवाह के समय दहेज लिया गया तो उसके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, बल्कि उस पर कानूनी कार्यवाही भी होगी।

मगर सवाल यह उठता है कि इन दहेज लोलुप आई०ए०एस० अफसरों पर यह सरकार कोई नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकती है, जबकि यह सरकार ही आई०ए०एस० अफसरों द्वारा आई०ए०एस० अफसरों के लिए बनायी गयी आई०ए०एस० अफसरों की सरकार है। इस बुराई को दूर करने के लिए तो आई०ए०एस० अफसरों में से ही किसी सुधारक को जन्म लेना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आई०ए०एस० अफसरों की बिक्री होती रहेगी और उनके खरीददार मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के चक्कर लगाते रहेंगे। **सुधा भाटिया**

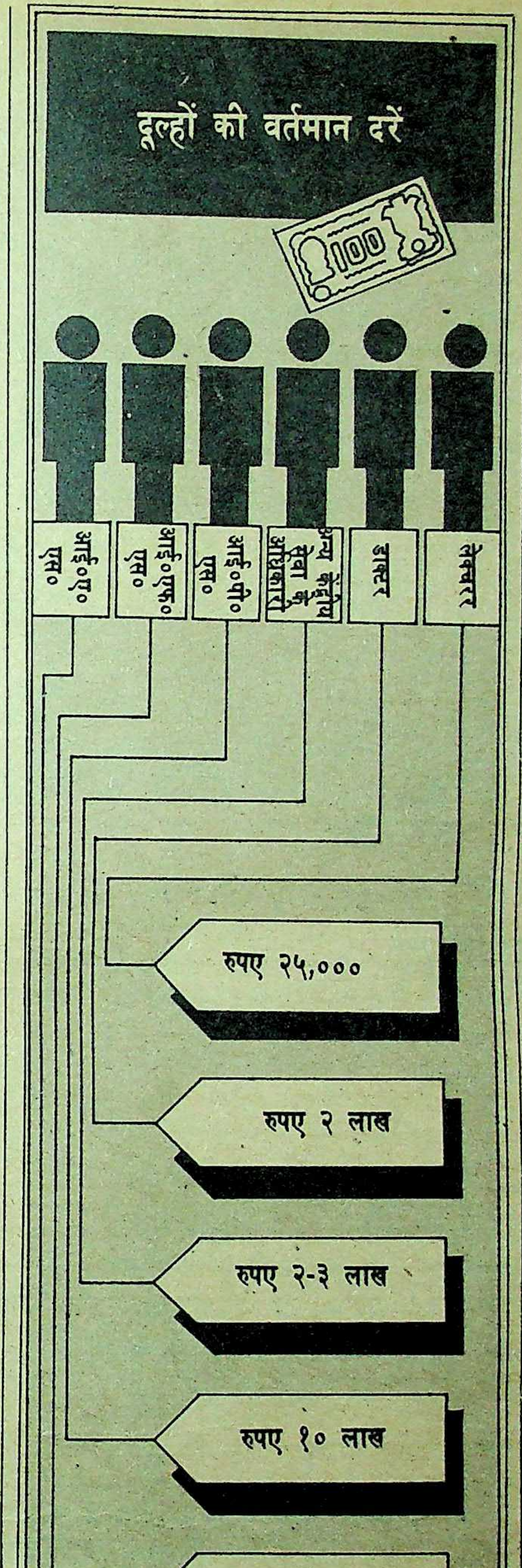

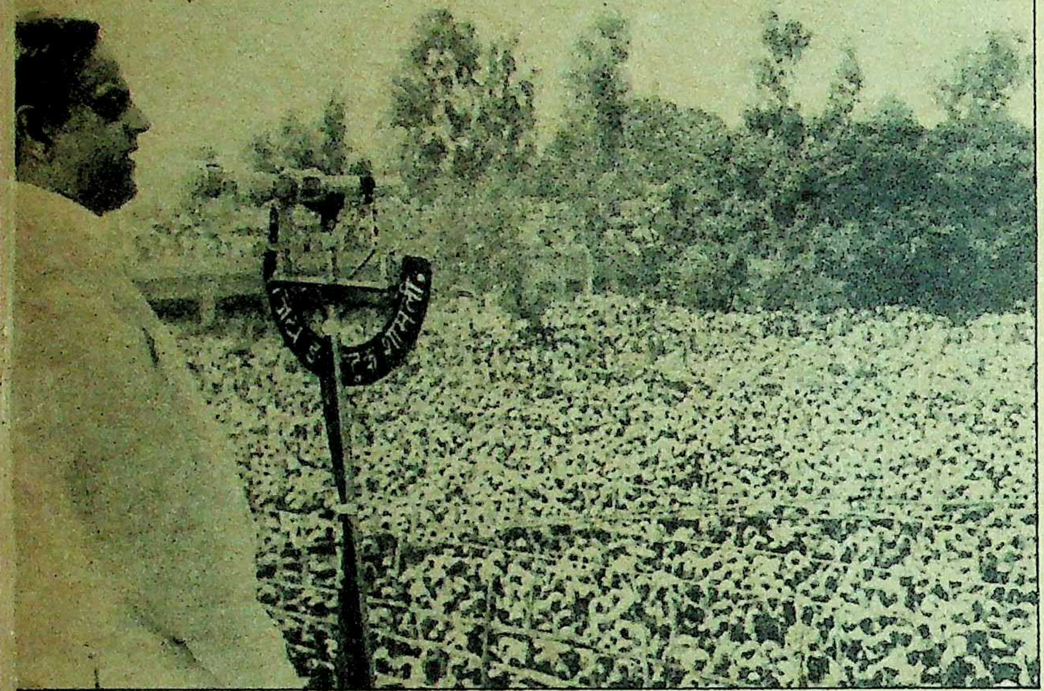

मंच मिला, समर्थन नहीं: सिसौली की किसान सभा में वीर बहादुर सिंह का भाषण

मुजफ्फरनगर किसान रैली

राजा का जवाब या अपना अपमान

वीर बहादुर सिंह ने सारी खुफिया रिपोर्टों को नजरंदाज करते हुए सिसौली मुजफ्फरनगर जा कर बड़ी राजनीतिक चतुराई दिखायी थी कि वह सरकार विरोधी किसान यूनियन के मंच से महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में यूनियन द्वारा एकत्र लाखों किसानों की सभा में किसानों की मांगों को मानने की घोषणा करके राजा वी०पी० सिंह द्वारा पैदा की गयी सरकार विरोधी लहर को मिटा देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। क्या इस सभा में मुख्यमंत्री को अपमानित होना पड़ा?

राजनीति के हर मोहरे पर बड़ी चालाकी से अपनी गोटियां फिट करनेवाले वीर बहादुर सिंह, पहली बार गच्चा खा गये हैं। इसी ११ अगस्त को सिसौली (मुजफ्फरनगर) में १० लाख से अधिक किसानों के सामने उन्हें बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। उनका अपमान किया भारतीय किसान यूनियन के बहुचर्चित नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने। यद्यपि इस बारे में वीर बहादुर सिंह कहते हैं, "मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। मेरे लिये तो यह सौभाग्य की बात थी कि लाखों किसानों के सामने मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। भीड़ उन्होंने (किसान यूनियन) जुटायी थी और डेढ़ घंटे तक मैं मंच पर रहा। बाजी तो मैंने जीती है, क्योंकि टिकैत ने खुद कहा कि सारा 'क्रेडिट' मुख्यमंत्री ले गये और मैं लुट गया।"

'क्रेडिट' किसे मिला और कौन लुटा। यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इस सारे प्रकरण पर वीर बहादुर मंत्रिमंडल के एक पूर्व प्रमुख सदस्य संजय सिंह कहते हैं, "किसानों की उस मीटिंग में जाकर वीर बहादुर ने सरकार और पार्टी दोनों की साख में बट्टा लगाया है। वीर बहादुर की मौजूदगी में मंच से महेन्द्र सिंह टिकैत और उनके लोगों ने प्रधानमंत्री तक के विरुद्ध अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया। इंटेलीजेंस के आई०जी० ने मुख्यमंत्री को मना किया था कि वह उस मीटिंग में न जायें, वहां कोई-न-कोई गड़बड़ी जरूर होगी, लेकिन वीर बहादुर ने अनसुना कर दिया। मीटिंग में गये थे शेर बनकर, लेकिन वहां से भागे गीदड़ की तरह।"

पृष्ठ भूमि: वास्तव में, भारतीय किसान यूनियन ने फरवरी १९८७ से सरकार के खिलाफ आन्दोलन छेड़ रखा है। इसी आन्दोलन के तहत पहली मार्च १९८७ को शामली में भड़की हिंसा में एक विद्युत गृह आग की भेंट चढ़ गया था। पथराव और पुलिस फायरिंग में होमगार्ड के एक जवान और दो किसानों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद किसान इतने आन्दोलित हुए कि उन्होंने २ अप्रैल, १९८७ को ५ लाख किसानों की सभा कर सरकार के विरुद्ध असहयोग की घोषणा कर दी।

किसान यूनियन की बढ़ती ताकत से घबरा कर वीर बहादुर सिंह ने विद्युत दरों में की गयी वृद्धि वापस ले ली। अपनी इस पहली जीत से किसान यूनियन के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत को काफी बल मिला। इस बीच जब हरियाणा में देवीलाल सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, तो महेन्द्र सिंह टिकैत ने यही मांग उत्तर प्रदेश में भी उठा दी।

इसी दौरान राजा विश्वनाथ प्रताप ने मुजफ्फरनगर के दौरे का कार्यक्रम घोषित कर दिया। वीर बहादुर सिंह को लगा कि अगर किसान यूनियन ने राजा को अपना मंच दे दिया, तो एक बहुत बड़ा वर्ग राजा समर्थक हो जायेगा। राजा का कार्यक्रम बनने से पूर्व महेन्द्र सिंह टिकैत उन्हें (राजा को) किसानों की सभा में आने का आमंत्रण भी दे चुके थे। बस, यहीं से वीर बहादुर सिंह ने टिकैत को 'पटाने' के लिए मोहरे बिछाने शुरू कर दिये।

सिसौली (टिकैत का गांव) के एक अध्यापक पूर्ण सिंह, लखनऊ में पायनियर मानटेसरी स्कूल चलाते हैं। वीर बहादुर सिंह के एक सलाहकार ने पूर्ण सिंह की भेंट मुख्यमंत्री से करा दी। पूर्ण सिंह ने वीर बहादुर से कहा, "मैं टिकैत को पटा लूंगा। वह न तो २६ जुलाई को मुजफ्फरनगर में होने वाली राजा की सभा में जायेगा और न ही अपना मंच उन्हें देगा। मैं टिकैत को इस बात पर भी राजी कर लूंगा कि वह किसानों की एक बहुत बड़ी सभा करे और उसमें आपको (वीर बहादुर सिंह) बुलाये।"

इस आश्वासन के बाद पूर्ण सिंह ने अपना 'काम' शुरू कर दिया। सिसौली जाकर उन्होंने टिकैत से कहा, "मुख्यमंत्री, किसानों की सभा में आकर आपकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। इसकी घोषणा वह किसानों के सामने करना चाहते हैं।" टिकैत ने हामी भर ली। पूर्णसिंह ने शर्त रखी, "तुम राजा की सभा में नहीं जाओगे।" टिकैत इसके लिए भी तैयार हो गये।

यह बात जब किसान यूनियन के दूसरे नेताओं को पता चली, तो उसमें से कुछ नाराज हो गये। यह वह लोग थे, जिनका झुकाव लोकदल या राजा साहब की ओर था। लेकिन टिकैत अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री के आदमी से वायदा कर लिया है। इसलिए पीछे नहीं

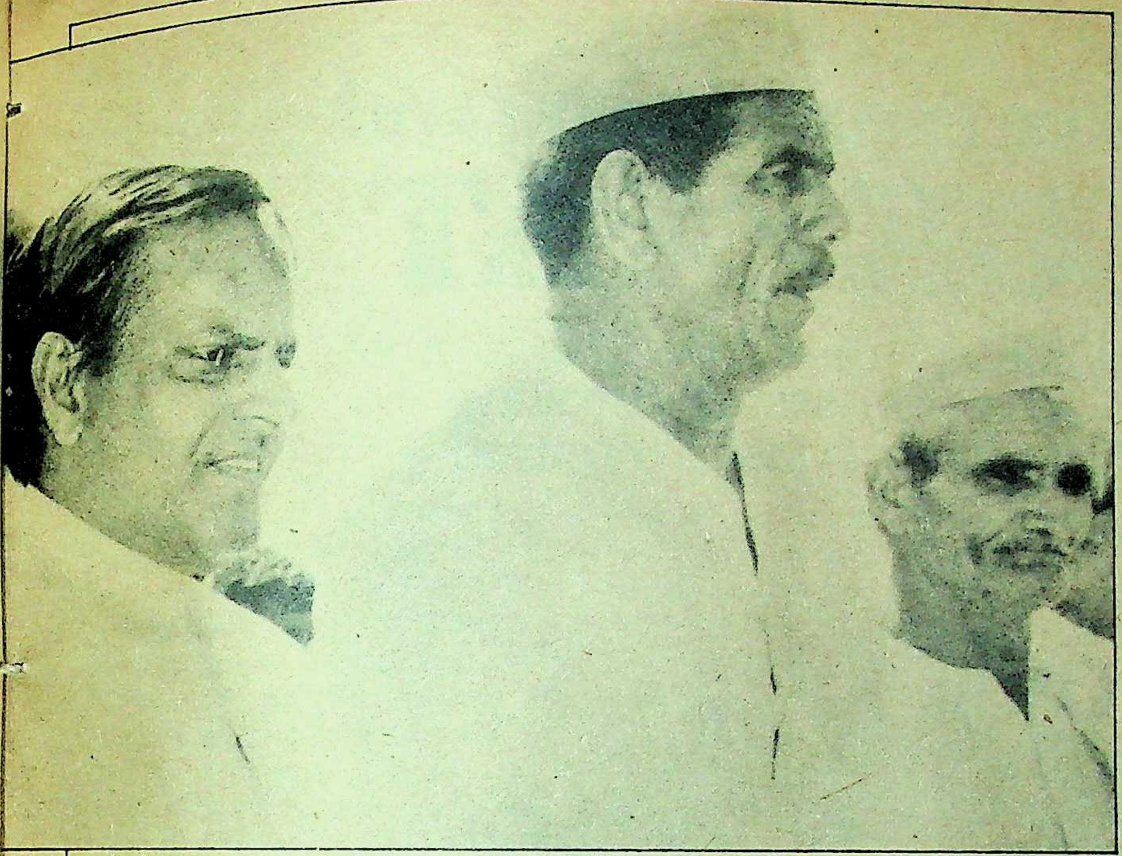

सुण ले वीर बहादुर... : मंच से ही वीर बहादुर सिंह (बायें) का मखौल उड़ाते महेन्द्र सिंह टिकैत (बीच में)

हटूंगा।" इसी के बाद किसान यूनियन में मतभेद पैदा हो गये। यूनियन के एक पदाधिकारी चौधरी सुखबीर सिंह ने खुले आम आरोप भी लगाया, "टिकैत ने वीर बहादुर से सात लाख रुपया लिया है।"

बहरहाल, ११ अगस्त की तारीख तय हो गयी। सिसौली में ही किसानों की सभा की तैयारी जोरदार ढंग से शुरू हो गयी। इस बीच टिकैत ने कुछ शर्तें रखीं। मसलन, किसानों की सभा में वीर बहादुर सिंह अकेले आयेंगे। सभा में न तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा लगेगा और न ही पुलिस और पी०ए०सी० रहेगी। सारे झंडे किसान यूनियन के ही लगेंगे। शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी यूनियन के वाल[illegible]ों पर होगी।

सिसौली, केराना विधान सभा क्षेत्र में आता है। वहां से प्रतिनिधित्व करने वाले हुकुम सिंह, वीर बहादुर की सरकार में राज्यमंत्री हैं। वीर बहादुर ने हुकुम सिंह से भी इस बारे में कोई राय नहीं ली। इसकी वजह यह थी कि हुकुम सिंह को विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थक माना जाता है। हुकुम सिंह के एक भाई चौधरी मुख्तियार सिंह तो किसान यूनियन को भरपूर सहयोग कर रहे हैं।

राजा की सभा: २६ जुलाई को मुजफ्फरनगर में विश्वनाथ प्रताप सिंह की विशाल सभा हुई। राजा ने अपने भाषण में किसानों की परेशानी और सूखे की समस्या के प्रति सरकार की उदासीनता का जमकर उल्लेख किया जिसके कारण उन्हें किसानों की काफी सहानुभूति मिली।

राजा की सभा के बाद किसान यूनियन में मतभेद और गहरे हो गये। यूनियन के तमाम नेता टिकैत पर दबाव डालने लगे कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अन्ततः यह तय हुआ कि वीर बहादुर सिंह को २० मांगों से संबंधित एक ज्ञापन दिया जाये तथा उन पर दबाव डाला जाये कि सभी मांगों को मानने की घोषणा वह सार्वजनिक रूप से इस सभा में करें। इन मांगों में कुछ इस प्रकार थीं— आन्दोलन के दौरान जिन किसानों के विरुद्ध मुकदमें दायर हुए हैं, वे वापस लिये जायें। पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित करते हुए किसानों के सभी ऋण माफ किये जायें। पानी का जलस्तर ऊपर उठाने के लिए नदियों पर बांध बनाये जायें। नलकूपों को लगातार १२ घंटे बिजली दी जाये। किसी नलकूप का कनेक्शन न काटा जाये। किसानों के लड़कों को स्कूलों और सरकारी सेवा में आरक्षण दिया जाये। ५५ साल से ऊपर की उम्र के किसानों को सरकारी पेंशन मिले। खाद और कृषि उपकरणों के मूल्य कम किये जायें। फसल बोने से पूर्व ही उसका भाव, लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाये। बाजार मूल्य पर मुआवजा दिये बिना किसी किसान की जमीन अधिगृहीत न की जाये।

२० सूत्रीय मांग की एक कापी पूर्ण सिंह के जरिए वीर बहादुर को भिजवा दी गयी। इसके बाद पूर्णसिंह ने टिकैत से कहा, "मुख्यमंत्री सभी मांगों के माने जाने की घोषणा करेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि उन्हें सबसे पहले भाषण करने दिया जाये।" टिकैत ने शर्त मान ली।

तभी इन्टेलीजेन्स विभाग के पुलिस महानिरीक्षक टी०एस० विष्ट ने मुख्यमंत्री के पास एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में कहा गया था, 'किसानों की इस मीटिंग में आपका जाना ठीक नहीं है। क्योंकि यूनियन के नेता किसी भी सुरक्षाकर्मी को मंच पर जाने नहीं देंगे। अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, उससे लगता है कि किसानों का एक बड़ा तबका सरकार विरोधी है, जिसमें ज्यादातर लोकदल और राजा के समर्थक हैं। यह लोग सभा में कोई भी गड़बड़ी कर सकते हैं। यूनियन के नेताओं में भी आपसी मतभेद है।'

इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। ११ अगस्त की दोपहर में सिसौली में सभा थी। १० अगस्त की शाम वीर बहादुर सिंह के एक खास सलाहकार डाक्टर यू०पी० सिंह की मौजूदगी में पूर्ण सिंह और मुख्यमंत्री की करीब ४० मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। ऐनेक्सी भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतरी कमरे में हुई इस बातचीत के दौरान सिसौली के ६ किसान नेता भी उपस्थित थे। पूर्ण सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि करीब ३०-४० लाख किसानों की भीड़ होगी। महेन्द्र सिंह टिकैत, सरकार का पूरा समर्थन करेगा।

११ अगस्त की दोपहर १२ बजे वीर बहादुर सिंह लखनऊ से हेलीकाप्टर द्वारा सिसौली के लिए रवाना हुए। उनके साथ एक सुरक्षा अधिकारी, सूचना-विभाग की वीडियो कैमरा टीम के अलावा पूर्ण सिंह थे।

ऐतिहासिक सभा: उधर सिसौली में १० अगस्त की शाम से ही किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गयी थी। किसानों के बीच जमकर यह प्रचार किया गया था कि वीर बहादुर सिंह उनके कर्जों की माफी की घोषणा करने आ रहे हैं। ११ अगस्त की सुबह तक सिसौली में करीब १० लाख की भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। लगभग ७ किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखायी पड़ रहे थे। आसपास के जिलों से ४०० से अधिक बसों में भरकर किसान वहां पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर जब सिसौली में लैण्ड किया, उस समय उनके स्वागत के लिए केवल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही हेलीपैड पर मौजूद थे। टिकैत या किसान यूनियन का कोई नेता वहां नहीं गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मंच तक पहुंचा दिया। इतना विशाल जनसमूह शायद वीर बहादुर को (राजीव गांधी की अनुपस्थिति में) पहली बार देखने को मिला था। वह गद्गद हो गये। मंच पर पहुंचते ही वीर बहादुर पूर्ण सिंह से फुसफुसाये, "टिकैत कहां है?"

पूर्ण सिंह ने मंच के नीचे फर्श पर बैठे टिकैत की ओर इशारा किया, "वह रहे।" मुख्यमंत्री को उम्मीद थी कि टिकैत उनके पास आकर अभिवादन करेंगें, लेकिन जब ४-५ मिनट तक टिकैत अपने स्थान से नहीं उठे तो, वीर बहादुर खुद उनके पास गये। हाथ मिलाया, फिर गले मिले। पर टिकैत अपने स्थान पर जमे रहे।

किसान का बेटा: वीर बहादुर ने भाषण की शुरुआत अपने को किसान का बेटा और जमीन का आदमी बताते हुए की। वह बोले, "मैं किसान का बेटा हूं। गरीबी में पैदा हुआ हूं। इसलिए जानता हूं कि खेत में अनाज पैदा करने वाला किसान आज कितना

Over 1,40,000 homes are now looking through the inner eye!

ALOKPAAT

The real-life, human interest Bengali monthly that's achieved a record-breaking 1,40,000 copies in just 6 months!

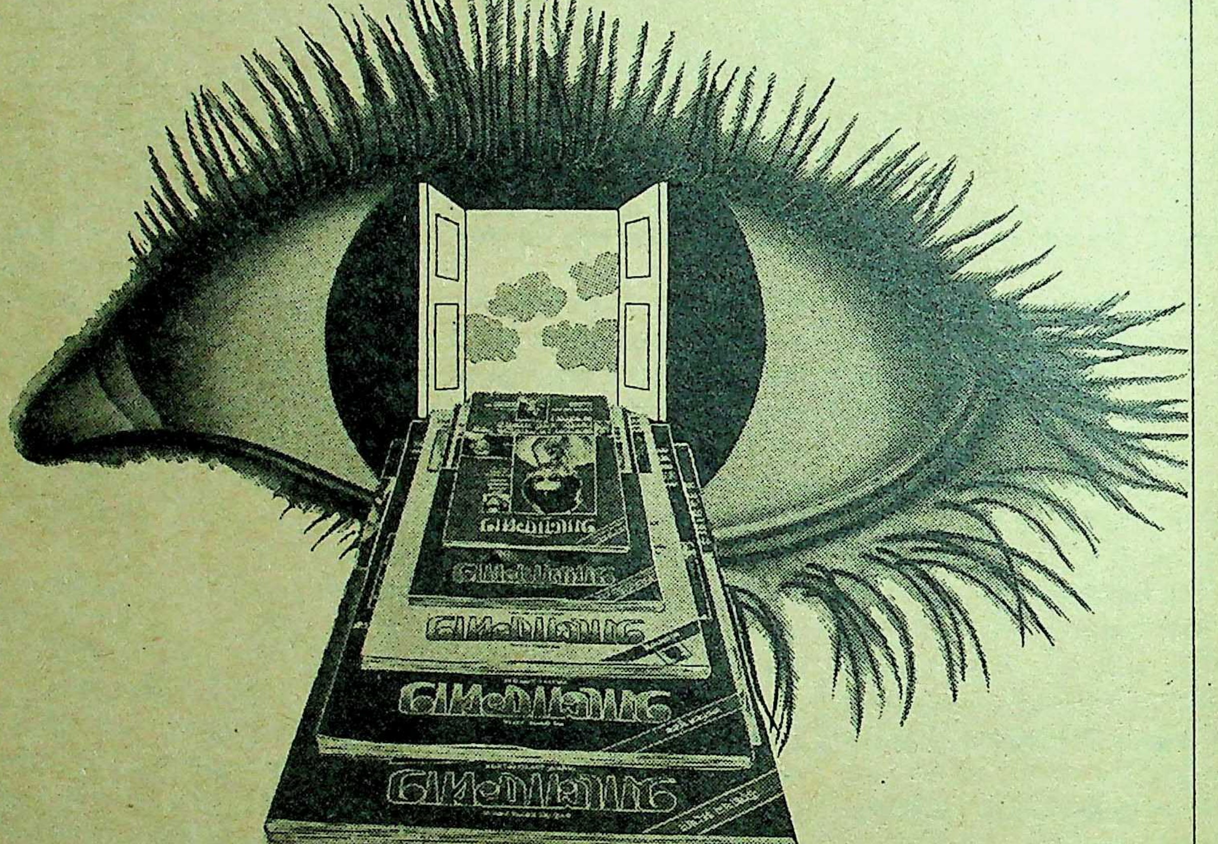

Within just six months of its launch, Alokpaat has reached into over 1.40 lakh homes—opening up an exciting new dimension in journalism. As the first investigative Bengali monthly to offer a unique insight into the real-life dramas that are intriguing the world every day—Alokpaat has captured the imagination and enthusiasm of thousands of men and women. It is this enthusiasm that has made Alokpaat a runaway success—with each new issue virtually 'sold-out' as soon as it hits the stands.

The Alokpaat growth curve—a unique picture of success

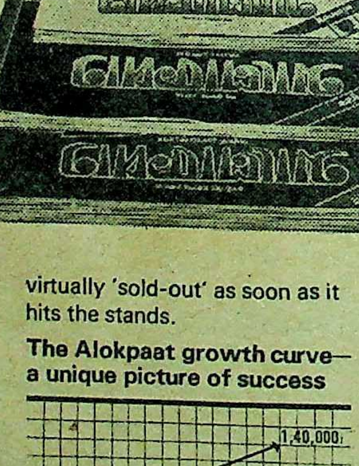

আলোকপাত

ALOKPAAT
A unique milestone
in Bengali journalism
—now a unique best-seller

MITRA PRAKASHAN
PRIVATE LIMITED
Allahabad

SAA/MP/13

दुखी है। जब तक उसे अनाज का सही मूल्य नहीं मिल जाता, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। किसानों की परेशानी को देखते हुए ही मेरी सरकार ने बिजली के रेट ३० रुपये से घटाकर साढ़े २२ रुपए किये हैं। मैं घोषणा करता हूं कि सूखे को देखते हुए किसानों की बकाया वसूली फिलहाल स्थगित की जायेगी।

अपने लगभग ४० मिनट के भाषण के दौरान वीर बहादुर सिंह घुमा-फिरा कर यही कहते रहे, "मेरी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। पिछले साल किसानों को खाद पर ५० प्रतिशत सबसिडी दी गयी थी। हम गांव में १० घंटे बिजली दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।"

कुश्ती आर-पार होगी : वीर बहादुर ने जब किसान यूनियन की मांग पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, तो टिकैत ने उनके सामने से माइक खींच लिया और ऊंची आवाज में बोले, "तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। सुणो, थमो (फिर) फेर मारे जाओगे। साफ-साफ सुणो, म्हांरी बात णा (न) सुणोगे, तो मारे जाओगे। इस देश का बेड्डा (बेड़ा) गरक होणे वाला है। सुण ले वीर बहादुर, तू भी काण (कान) खोल कर सुण ले और कह दे अपणे प्रधानमंत्री से और सभी गांधियों से कह दे, अब किसाण सड़कों पर आ गया है। वह झुकेगा नहीं। दबकर समझौता नहीं करेगा। अब तो कुश्ती आर-पार होवैगी।" इतना कहकर महेन्द्र सिंह टिकैत फिर अपनी जगह जाकर बैठ गये। तभी टिकैत के छोटे भाई भोपाल सिंह ने माइक संभाल लिया। वह बोले, "इस तरह के सरकारी भाषण तो हम चालीस साल से सुनते आ रहे हैं। वीर बहादुर सोचते हैं कि किसान यूनियन की इस रैली में आकर उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रभाव समाप्त कर दिया है, तो यह उनकी भूल है। जब तक पूरे प्रदेश के किसानों के कर्जे माफ नहीं होते, तब तक हमारा सरकार से असहयोग आन्दोलन चलता रहेगा।"

भोपाल सिंह के हटते ही टिकैत फिर माइक पर आ गये और गुस्से में बोले, "यह जो पूर्ण सिंह बैठ्या है, एक महीने से मेरे पीछे-पीछे दुम हिला रहा था। कहता था वीर बहादुर ने सारी मांगें मान ली हैं। मैं कहता हूं कि राजनीतिक चमचों सावधान हो जाओ, दलालों होश में आओ अब महाभारत होगा। हमारे रथ को खींचने वाला कोई और ही है" (शायद इशारा राजा साहब की ओर था)।

टिकैत का इतना कहना था कि भीड़ से नारेबाजी शुरू हो गयी। दलाल को नीचे उतारो। मुख्यमंत्री हां या ना में जवाब दो। अभी तक भीड़ यह समझ रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठे पूर्ण सिंह कोई सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन जब लोगों को यह पता चला कि यही पूर्ण सिंह है, तो उन्हें मंच से नीचे उतार दिया गया। टिकैत तीसरी बार माइक पर आ गये।

उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। वह गरजे, "हम कमजोर नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हंगामें का केन्द्र उत्तर प्रदेश बने तथा लखनऊ और दिल्ली की गद्दी हिल जाये। इन्दिरा गांधी ने तो मिल मालिकों का २५ करोड़ का कर्जा माफ किया था। आज देश में दौलत की कमी नहीं है। इसीलिए यहां का पैसा लोग विदेशों में जमा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तुम कान खोल कर सुन लो। कह दो अपने राजीव से, वह विदेश में जमा पैसा निकलवा कर किसानों की मांग मान ले। यह पैसा किसानों पर खर्च हो।"

टिकैत ने चेतावनी पूर्ण शब्दों में कहा, "अब यह बरदाश्त नहीं होगा कि देश की जनता, जिसमें किसानों की संख्या ८० प्रतिशत से ज्यादा है, को सरकार बेवकूफ बनाती रहे और २० प्रतिशत जनता से संबंध रखने वाले लोग राज करें। आज हम किसान घर से बेघर हो गये हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि देश का बेड़ा गर्क हो। जब हरियाणा की सरकार ने किसानों के सभी कर्जे माफ कर दिये हैं तो यू०पी० की सरकार क्यों माफ नहीं कर सकती। किसान के पेट की ज्वाला अब बांहर आ चुकी है। सरकार यह न समझे कि वह लखनऊ और दिल्ली की कोठियों में बैठकर किसानों का शोषण करती रहेगी। मुख्यमंत्री को यहां 'हां' या 'ना' में जवाब देना होगा, बोल मुख्यमंत्री तू हमारे कर्जे माफ करता है या नहीं। बोल यहीं ऐलान कर।"

मुख्यमंत्री, अभी तक सिर झुकाये सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें स्वप्न में भी यह उम्मीद नहीं थी कि भरी सभा में उन्हें इस तरह अपमानित होना पड़ेगा। कुछ सोचते हुए वह उठे और माइक पर बोले, "इस बारे में हम कैबिनेट की मीटिंग में विचार करेंगे। तब 'हां' या 'ना' में उत्तर देंगे। हमें एक महीने का समय चाहिए।"

"नहीं देंगे, नहीं देंगे", चारों ओर से किसानों की आवाज आयी। तमाम लोग खड़े हो गये। "घेर लो, जाने न दो, धोखेबाज है" जैसी आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। लेकिन टिकैत ने स्थिति को गंभीर होने से बचा लिया। वह बोले, "मुख्यमंत्री आज यहां हमारे मेहमान के रूप में आये हैं। मेहमान का सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसलिए हम उन्हें एक महीने की जगह दो महीने का टाइम देते हैं।" इस ऐलान के साथ ही चारों ओर से आवाज आयी, "दे दो, दे दो।"

वीर बहादुर सिंह पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुके थे। एक घंटा ४० मिनट तक उस चिलचिलाती धूप में मंच पर बैठे अपमानजनक बातें सुनते रहे। जब बातें सहन नहीं हुईं, तो वह उठे और तेजी से वापस हो लिये। लेकिन टिकैत ने यह कह कर रोक लिया, "आप हमारे मेहमान हो। आपके लिए असली घी का हलुआ और गर्म दूध का इंतजाम हमने किया है। उसे खाकर जाइये।"

"नहीं, नहीं, बहुत हो गया, कहते हुए वीर बहादुर तेजी से हेलीपैड की ओर बढ़ लिये। इसी के साथ चारों ओर से नारे लगे "चौधरी टिकैत जिन्दाबाद, वीर बहादुर मुर्दाबाद।" "राजीव गांधी होश में आओ, देश का पैसा देश में लाओ।"

बाद में पूरन सिंह ने अखबारों में बयान देकर साफ-साफ कहा कि चौधरी टिकैत ने सरासर झूठ बोला है। पहले तय हुआ था कि मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह बिजली की दर कम करने, झूठे मुकदमें वापस लेने और बिजली बिलों के भुगतान में विलंब शुल्क न लेने—इन तीन रियायतों की घोषणा करेंगे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे तो उनके हाथों में २० मांगों को मानने की घोषणा करने के लिए मांग पत्र पकड़ा दिया गया। मुख्यमंत्री ने फिर भी इनमें से ११ मांगो को मानने की घोषणा की, फिर भी यह हंगामा हो गया।

लखनऊ पहुंचकर वीर बहादुर को लगा कि दिल्ली और लखनऊ के अखबारों में उनकी इस ऐतिहासिक रैली का समाचार कहीं तोड़-मरोड़ कर न छप जाये। उन्होंने फौरन सूचना विभाग को आदेश दिया, "रैली का फोटो लखनऊ के सभी अखबारों को भेजा जाये।" सूचना विभाग में हड़कम्प मच गयी। वहां का कोई फोटोग्राफर रैली में नहीं गया था। १२ और १३ अगस्त को जब लखनऊ के अखबारों में उस रैली के फोटो नहीं छपे, तो फिर मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग को आड़े हाथों लिया। नतीजतन वीडियो कैसेट से टी०वी० पर रैली के कुछ दृश्य 'स्थिर' करके उनके चित्र लिये गये। लेकिन ये चित्र इतने अच्छे नहीं थे कि अखबारों में छप सकें। सूचना विभाग ने मेरठ टेलेक्स कर वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जैसे भी हो चित्रों की व्यवस्था कर लखनऊ भेजा जाये। इस बीच (१३ अगस्त) सूचना विभाग को यह जानकारी मिली कि 'माया' के लखनऊ ब्यूरो में, रैली के चित्र आ गये हैं। विभागीय अधिकारियों ने काफी अनुनय-विनय कर 'माया' से चित्र प्राप्त कर उन्हें दिल्ली तथा लखनऊ के समाचार पत्रों में १४ अगस्त को छपवाया।

—लखनऊ ब्यूरो

एस० मुजम्मिल हुसैन।

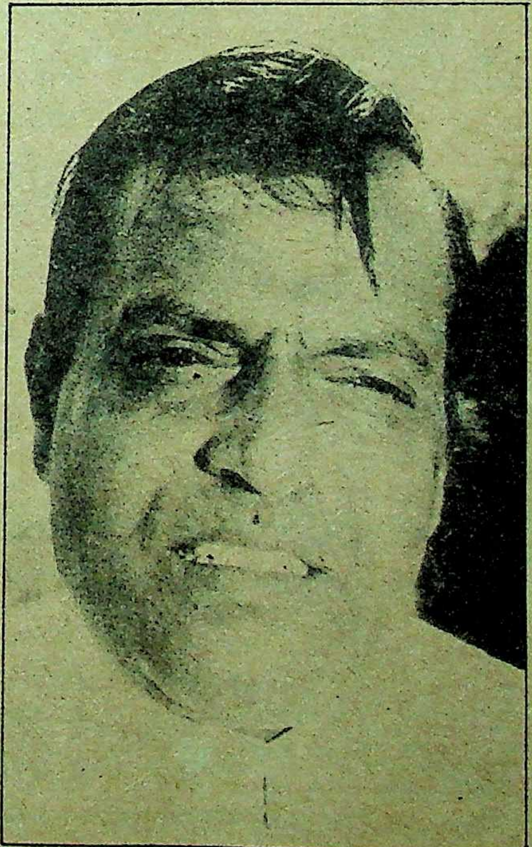

गच्चा खा गये : पसीने से तरबतर वीर बहादुर सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

प्रस्तुत हैं......

तोहफा भेंट योजना

हर महिने ४०० शानदार भेंट जितने का एक अनोखा मौका!

यह हकीकत हैं! तोहफा भेट योजना में शामील हो जाईये और शानदार भेंट आसानी से पाईये। आप की सिर्फ रु. ५०००/– की पूंजी, जो नेशनलाईझ बॅंक की तरफ से दिये जानेवाले कॅश सर्टिफीकेट के रूप में संपूर्ण सुरक्षित हैं, जो आप को हर महिने कई फायदे देगी। आपकी पुंजी आप सीधे ''युनियन बॅंक A/C सीएफसी'' के नाम हमें भेज सकते हैं।

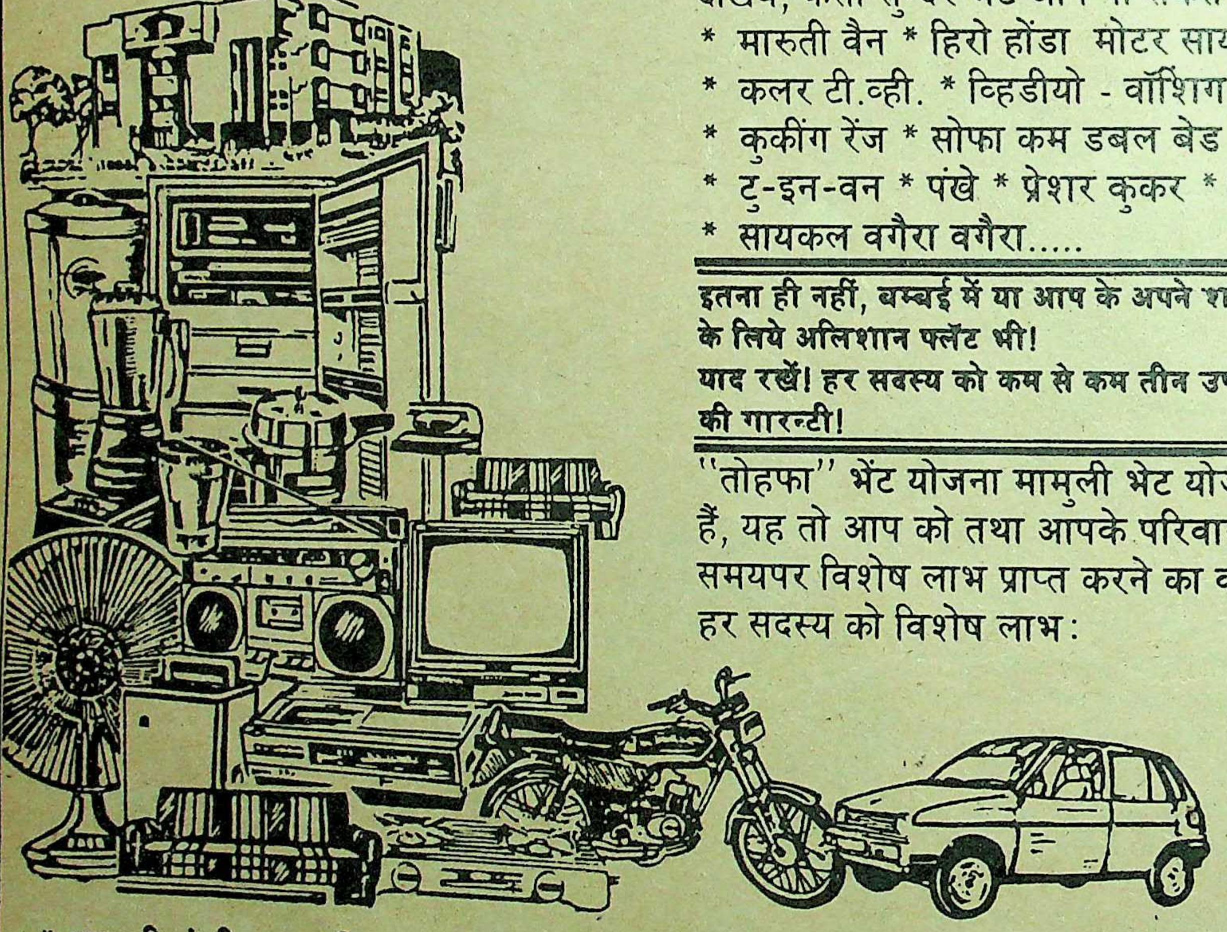

देखियें, कैसी सुन्दर भेंट आप पा सकते हैं!
* मारुती वैन * हिरो होंडा मोटर सायकल
* कलर टी.व्ही. * व्हिडीयो - वॉशिग मशीन
* कुकींग रेंज * सोफा कम डबल बेड
* टु-इन-वन * पंखे * प्रेशर कुकर * मिक्सर
* सायकल वगैरा वगैरा.....

इतना ही नहीं, बम्बई में या आप के अपने शहर में रहने के लिये अलिशान फ्लॅट भी!

याद रखें! हर सदस्य को कम से कम तीन उपहार मिलने की गारन्टी!

''तोहफा'' भेंट योजना मामुली भेट योजना नही हैं, यह तो आप को तथा आपके परिवार को सही समयपर विशेष लाभ प्राप्त करने का वरदान हैं। हर सदस्य को विशेष लाभ :

*** आपकी पुंजी पर मासिक ब्याज * विनामूल्य ॲक्सीडंट पॉलीसी * मकान के लिये खास कर्ज**

आप कुछ ज्यादा ही जानना चाहते है न? तो फिर सम्पर्क करें :

पूना ब्रान्च :
११३, एम्.जी. रोड,
हर्मेस्नॉक, पूना–१.

कॉन्सॉलिडेटेड फायनान्स कॉर्पोरेशन,
१, बन्सारी अपार्टमेंट, ३० वा रास्ता,
पाली नाका, बम्बई-४०० ०५०. फोन: ६४० ७०५९

क्या यह जगन्नाथ मिश्र की वापसी है?

डा० जगन्नाथ मिश्र को सूखा-अकाल समिति का संयोजक बनाकर राजीव गांधी ने कमलापति त्रिपाठी की तरह एक और विद्रोही का मुंह बंद करने की कोशिश की है या वास्तव में उन्होंने डा० मिश्र को सत्ता और संगठन में और भी महत्वपूर्ण पद देने का मन बना लिया है

आज से चार साल पूर्व का अगस्त महीना डा० जगन्नाथ मिश्र के लिए जिस तरह राजनीतिक दुर्भाग्य के दौर की शुरुआत लेकर आया था ठीक उसी के विपरीत १९८७ का अगस्त महीना जगन्नाथ मिश्र के लिए बेहतर संभावनाओं के संकेत दे गया। क्या जगन्नाथ मिश्र का राजनीतिक-अकाल अब खतम होने पर है, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर तब से है जबकि इंका आलाकमान ने अपनी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की सूखा-अकाल से निपटने के लिए गठित तीन समितियों में से एक का संयोजक जगन्नाथ मिश्र को बना दिया। इस मनोनयन को लेकर पटना के राजनीतिक अखाड़ों में बहस-मुबाहसों का दौर जारी है। जगन्नाथ खेमा जहां इत्मीनान में है कि संदेह और भ्रम में विगत चार वर्षों से जिस तरह वे लोग उलझे थे वह दौर अब कट चुका है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे अंदरूनी रूप से सशंकित हैं कि जगन्नाथ मिश्र का नाम सुनते ही भड़क उठनेवाला आलाकमान अचानक जगन्नाथ मिश्र पर इतना कृपालु कैसे हो गया कि अकसर मंत्रणा के लिए जगन्नाथ मिश्र तलब किये जा रहे हैं। तिस पर तुर्रा पड़ा यह कि सूखा-समिति में भी ले लिये गये। ऊपर से बिहंस कर यह कहता हुआ दुबे-खेमा कि जगन्नाथ मिश्र को महज यह मुलम्मा दिया गया है भीतर-ही-भीतर बेचैन है। नतीजतन, अफरातफरी मची हुई है। और अपने-अपने कारणों से अरसे से छितराये पड़े जगन्नाथ विरोधी छोटे-छोटे उपग्रह अब फिर एक दूसरे का चक्कर तेजी से लगाना शुरू कर चुके हैं।

८ और ९ अगस्त को तमाम जगन्नाथ विरोधी गुट पूरी तत्परता से गले मिलने का सार्वजनिक प्रदर्शन भी कर गये। ८ अगस्त को सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर ने पटना के रवींद्र भवन में सेवा दल का सम्मेलन करवाया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री दुबे ने किया और ठीक अगले दिन यानी ९ अगस्त को युवा इंका का वृहद सम्मेलन श्याम सुंदर धीरज ने श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित किया। इसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया।

आखिर इतनी आपाधापी में ये सारे कार्यक्रम क्यों आयोजित हुए इसका खुलासा करते हुए इंका के अखाड़िये कहते हैं कि इंका के राष्ट्रीय खजांची सीताराम केसरी की पहल के तहत यह सब कुछ हुआ। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद से केसरी का पानी बिलकुल उतरा हुआ है। नतीजतन, वह दोबारा फिर से कुछ हलचल कर आलाकमान को अपनी मौजूदगी का अहसास कराने को बेचैन हैं। पर उनका आदि शिष्य तारिक अनवर ही उनसे कुपित था। पटना में बस युवा इंका के अध्यक्ष श्याम सुंदर धीरज ही केसरी के नाम लेवा रह गये थे। तारिक और धीरज में भी अरसे से ठनी हुई थी। बहरहाल, केसरी ने अपनी टोपी को जरा और तिरछा कर फिर से एक बार अपने बिछुड़े शिष्यों को बटोर कर कुछ करने का जोर लगाया। तारिक, धीरज को आखिरकार केसरी ने गले मिलवा कर ही दम लिया। तभी तारिक युवा इंका के कार्यक्रम में शरीक होने को तैयार हो सके। केसरी ने दुबे को समझाया कि जगन्नाथ की तेजी से वापसी के आसार स्पष्ट हैं और ऐसे में एक बार फिर जगन्नाथ मिश्र को सिंह द्वार में प्रवेश से रोकने के लिए एकजुट होना होगा। अंधे को क्या चाहिए दो आंख। सो दुबे को घर बैठे यह समर्थन जब केसरी सौंपने की पेशकश कर गये, तो गद्गद भाव से दुबे ने युवा इंका सम्मेलन के अपने भाषण में केसरी को 'मेरे पुराने मित्र केसरीजी' कहकर कृतार्थ किया।

अगस्त के दूसरे सप्ताह में अचानक एक ही समय दुबे व जगन्नाथ मिश्र को आलाकमान ने दिल्ली में याद किया। दोनों की इस यात्रा से शिगूफे और गरम हो गये। १३ अगस्त तक तो यहां तक अटकलें गरम थीं जिस तरह १९८३ में जगन्नाथ मिश्र पंद्रह अगस्त का झंडा गांधी मैदान में नहीं फहरा सके, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए दुबे भी शायद ही इस बार गांधी मैदान तक पहुंच सकें।

दुबे अभी बच गये हैं—राजनीतिक पंडित बिहंस कर फलाफल निकाल रहे हैं। इंका के एक घिसे हुए खिलाड़ी कहते हैं कि अक्तूबर महीने से दुबे अपना दैनिक पटना से निकालने ही जा रहे हैं। अगर चार-छह महीने में हट भी गये, तो पटना में दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के दैनिक चलते रहेंगे। दुबे ने जगन्नाथ मिश्र के जनता-दरबार में भक्तजनों की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार और कुछ निकम्मे और भ्रष्ट मंत्रियों की छुट्टी करने का पुराना राग फिर से अलाप दिया है। लिहाजा, अधिकांश विधायक दिन को दुबे के दरबार में और रात को चुपचाप जगन्नाथ मिश्र के दरबार में कवायद कर रहे हैं। एक इंका विधायक रोचक टिप्पणी करते हैं— "आजकल हमें 'ओवर टाइम' करना पड़ रहा है। दुबे बाबा के यहां और जगन्नाथ मिश्र के यहां भी।"

छाया : अमरेंद्र दुबे

—विकास कुमार झा

व्यक्तिगत रंजिश या गहरी साजिश? : निर्मल महतो का पार्थिव शरीर और उसके पीछे खड़े उनके पिता, बहन एवं समर्थक

झारखंड मुक्तिमोर्चा

मोर्चेबंदी की राजनीति

जमशेदपुर में ठेकेदारों से बाकायदा चौथ वसूलने के लिए कुख्यात वीरेन्द्र सिंह ने क्या निजी रंजिश के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की दिन-दहाड़े हत्या कर दी या इसके पीछे मोर्चा को कमजोर करने के लिए कोई गहरा षड्यंत्र रचा गया था? इस काण्ड में बिहार के सिंचाई व संसदीय कार्य मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह का नाम क्यों लिया जा रहा है? महतो की हत्या के बाद मोर्चा के एक विधायक सूरज मंडल द्वारा सदन के उपनेता पद से इस्तीफा देने के बाद क्या मोर्चा बिखरने लगा है? आदिवासियों की समस्यायों को सुलझाने के लिए बना झारखंड मुक्ति मोर्चा आज खुद किन आंतरिक समस्याओं में उलझ गया है?

"झारखंड मुक्तिमोर्चा के नेता और विधायक अपने अध्यक्ष निर्मल महतो के खून के सवाल पर झारखंड आंदोलन को एक कारगर रफ्तार तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। क्या निर्मल महतों की शहादत यों ही बेकार चली जाएगी?" झारखंड मुक्तिमोर्चा के एक सक्रिय कार्यकर्ता की यह मासूम टिप्पणी और कसक मोर्चा के आम कार्यकर्ताओं में अपने नेतृत्व पर बढ़ती अनास्था का एक चुभता नमूना है।

८ अगस्त की सुबह जमशेदपुर में हुई झारखंड मुक्तिमोर्चा के युवा तुर्क अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या ने एकबारगी पूरे दक्षिण बिहार को आंदोलित करके रख दिया है। लगातार रांची, जमशेदपुर सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश शहर और छोटे-छोटे कस्बे तक विरोधस्वरूप बंद रहे और उत्तेजित आदिवासियों ने तो तीन-चार लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया। गम्हरिया में एक इंका कार्यकर्ता अमरेंद्र सिंहा, डुमरिया में एक वनरक्षक प्रयाग पासवान और आदित्यपुर में सतीश शर्मा नामक एक नौजवान की हत्या कर.दी गयी। दक्षिण बिहार में आदिवासियों के महतो जाति बहुल गांव में गजब का गुस्सा है। रांची—जमशेदपुर में हजारों की तादाद में जुलूस निकले, पर निर्मल की हत्या से उपजे आक्रोश को झारखंड मुक्तिमोर्चा की अगली पंक्ति के नेता सही ढंग से संभाल कर उसे दिशा नहीं दे सके। इस बात की पीड़ा मोर्चा के आम कार्यकर्ताओं को आहत किए हुए है। मोर्चा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि मोर्चा के नेताओं में खुद इतनी उखाड़-पछाड़ मची हुई है कि कोई विधायक उससे उबर नहीं पा रहा है। वाकई आदिवासियों का यह जुझारू राजनीतिक संगठन संक्रमण के कड़े दौर से गुजर रहा है। निर्मल महतो की हत्या ने तो उसे और भी झकझोर कर रख दिया है।

हत्यारे रामाश्रय के आदमी हैं: सूरज मंडल

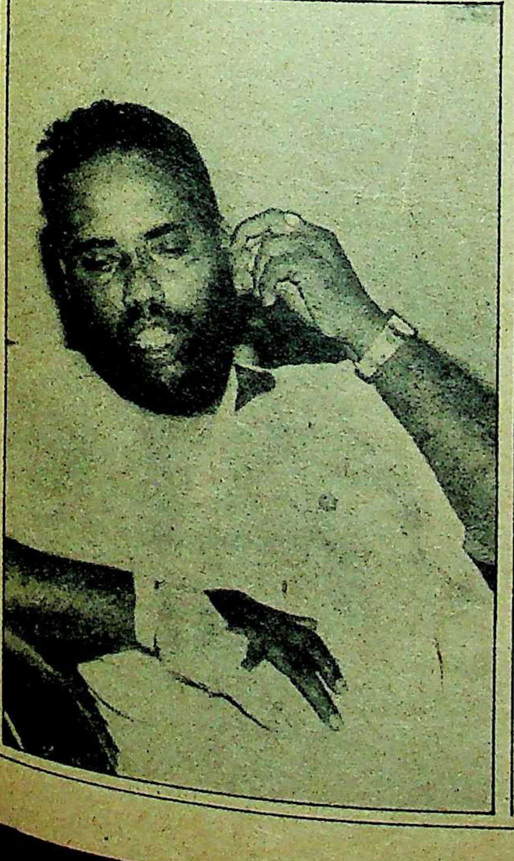

विवाद हल हो जायेंगे: शिबू सोरेन

घटना:

पोड़ैयाहाट से झारखंड मुक्तिमोर्चा के विधायक सूरज मंडल के हाथ में गोली का जख्म अभी तंक नहीं भरा है। ८ अगस्त की सुबह के उस खूनी हमले में सूरज मंडल तो बाल-बाल बच गये पर उनकी आंखों के सामने उनके अध्यक्ष निर्मल महतो ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। उस हादसे का आंखों देखा हाल बताते हुए सूरज कहते हैं कि ५ अगस्त को रांची में झारखंड मुक्तिमोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक थी। मोर्चा के सारे विधायक रांची आये हुए थे। अगले दिन यानी ७ अगस्त की शाम मैं, निर्मल महतो, मोर्चा के दो कार्यकर्ता बाबूलाल सोय और शिवाजी राय तथा इंका के पूर्व विधायक ज्ञानरंजन जमशेदपुर के लिए चल दिए। वहां हमें एक मित्र अवतार सिंह तारी की मां के श्राद्ध में शामिल होना था। रात के साढ़े दस बजे हम सब जमशेदपुर पहुंचे। विचार हुआ कि चलकर टिस्को गेस्टहाउस, जो चमरिया गेस्टहाउस के नाम से मशहूर है, में देखें अगर वहां जगह होगी तो ठहर जायेंगे। पूर्व विधायक ज्ञानरंजन अक्सर उस गेस्ट हाउस में ठहरते रहे हैं। गेस्ट हाउस में दो कमरे मिल गये। अगले दिन ८ अगस्त की सुबह मोर्चा के कार्यकर्ता हमलोगों से मिलने और कुछ इंका कार्यकर्ता ज्ञानरंजन से मिलने आ गये थे। साढ़े नौ बजे एक मजिस्ट्रेट टी०एन० शर्मा आये जो निर्मल महतो से बातें करने लगे। बहरहाल, तैयार होकर मैं और निर्मल महतो गेस्ट हाउस के बाहर आये। निर्मल के एक रिश्तेदार कालीपद महतो ने हाल ही में एक गाड़ी खरीदी थी। उसने हम दोनों से अनुरोध किया कि चलकर कारखाने में उस गाड़ी को देख लें। गाड़ी को देखने के बाद हमने तय किया कि इस गाड़ी को दुरुस्त कराकर 'झारखंड क्रांतिरथ' बनायेंगे। गाड़ी देखकर हम वापस गेस्ट हाउस आ गये। फिर अपने कार्यकर्ता शिवाजी राय को सोनारी स्थित "झारखंड मुक्तिमोर्चा" के कार्यालय जीप लाने के लिए भेज दिया। तब तक दिन के बारह बज गये थे। जीप आ गयी तो हमलोग सरदार अवतार सिंह तारी के घर जाने को निकले। ज्ञानरंजन उस समय तक अपने कमरे में ही थे। पोर्टिको से हम निकल ही रहे थे कि देखा स्थानीय ठेकेदार सुनील सिंह और शंकर सिंह अपनी गाड़ी से उतर कर आ रहे हैं। वे लोग भी सरदार तारी के घर ही जा रहे थे। हम उन लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में डी०इ०ए० २५४४ नंबर की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से चार-पांच लोग उतरे। निर्मल महतो ने उनमें से दो को पहचानते हुए कहा, "ये वीरेंद्र सिंह के दोनों भाई पंडित और पप्पू हैं।" इसी बीच दो स्थानीय पत्रकार एन०के०सिंह और सुनील बनर्जी भी आ गये। वीरेंद्र सिंह जमशेदपुर का एक कुख्यात रंगबाज है। वह अपने दोनों भाइयों के आने से पूर्व टिस्को गेस्ट हाउस की लाबी में बैठा था। सरदार तारी के घर जाने में हमें विलंब हो रहा था लिहाजा, हमने आई०के० चौधरी से कहा कि ज्ञानरंजन को कमरे से बुला लायें। चौधरी के जाते ही पीछे से वीरेंद्र सिंह अपने दोनों भाइयों सहित आया और एकबारगी चिल्ला पड़ा, "इन दोनों को आज यहीं उड़ा दो।" पहले तो हम समझ ही नहीं पाये कि उसका इशारा किसकी तरफ है क्योंकि हम दोनों के अलावा सुनील सिंह और शंकर सिंह भी वहीं खड़े थे। पर अगले ही क्षण जबतक हम संभलें हमलावर निर्मल और मुझ पर टूट पड़े। बचाव के लिए बदहवासी में निर्मल ने सुनील सिंह को कसकर पकड़ लिया ताकि हमलावर उनपर गोली न चला सकें। वीरेंद्र का भाई पप्पू जो निर्मल को सुनील से खींचकर अलग कर रहा था, मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया। निर्मल महतो भागने लगे कि तभी वीरेंद्र सिंह ने उनपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। निर्मल खून से लथपथ होकर गिर पड़े। फिर, ज्योंही मैं उन्हें उठाने को दौड़ा कि एक गोली सनसनाते हुए मेरे दायें हाथ में आकर धंस गयी। हत्यारे भाग रहे थे कि सुनील सिंह ने एक फायर भागते हत्यारों पर किया। वहां मौजूद सारे लोग हतप्रभ थे। ज्ञानरंजन फूट-फूट कर रोने लगे। बाहर खड़ी जीप पर हमने घायल निर्मल महतो को रखा और अस्पताल की तरफ चले। लेकिन आधे रास्ते में ही निर्मल महतो ने दम तोड़ दिया।

आखिर वीरेंद्र सिंह ने निर्मल महतो की हत्या इस तरह खुलेआम क्यों की? स्थानीय लोग इसका खुलासा करते हुए कहते हैं कि निर्मल और वीरेंद्र की रंजिश पुरानी थी। वीरेंद्र सिंह जमशेदपुर में अरसे से आतंक मचाये हुए था और बाकायदे ठेकेदारों से चौथ वसूलता था। निर्मल महतो वीरेंद्र की इन हरकतों का विरोध करते थे। कुछ लोगों के मुताबिक

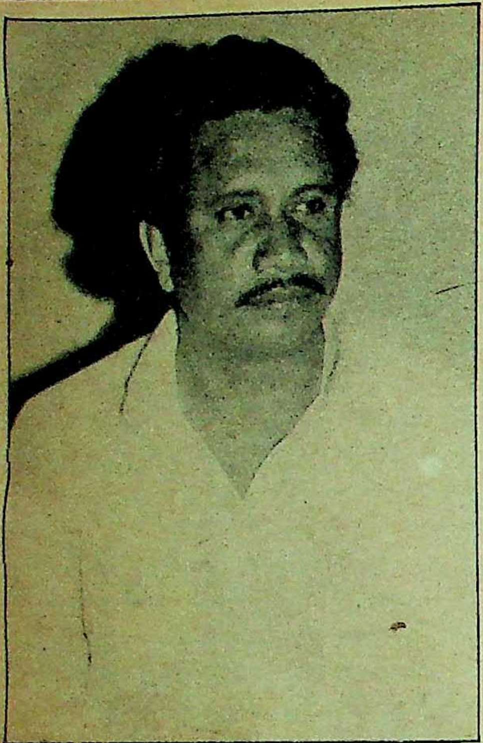

झारखंड आंदोलन जारी रहेगा: देवीधन बेसरा

डेविड का आचरण ठीक नहीं था :सालखान सोरेन

ठेकेदारी में हिस्से को लेकर निर्मल व वीरेंद्र में अकसर तनाव रहता था। गत ८ नवंबर, १९८६ को अचानक सोनारी में वीरेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। एफ०आई०आर० में वीरेंद्र ने निर्मल महतो सहित झारखंड मुक्तिमोर्चा के छह-सात कार्यकर्ताओं का नाम दर्ज कराया था। इस सिलसिले में पुलिस ने निर्मल महतो सहित मोर्चा के छह कार्यकर्ताओं की सम्पत्ति को कुर्क भी किया था। उसी समय से वीरेंद्र सिंह को एक सुरक्षा प्रहरी भी दिया गया। झारखंड मुक्तिमोर्चा के नेता इस बात का खंडन करते हैं कि वीरेंद्र सिंह पर हुए हमले में निर्मल महतो का हाथ था। इन लोगों के मुंताबिक निर्मल तो उस दिन जमशेदपुर में थे ही नहीं।

मोर्चा के आहत विधायक सूरज मंडल ने इस हादसे को लेकर सिंचाई व संसदीय कार्य मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह पर बेहद संगीन आरोप लगाये। सूरज के मुताबिक वीरेंद्र रामांश्रय सिंह का पालतू गुण्डा रहा है। तकरीबन आठ वर्ष से भी अधिक रामाश्रय प्रसाद सिंह सिंहभूम में बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री हैं। इस अवधि में रामाश्रय ने वीरेंद्र के जरिये काफी पैसे उगाहे। सूरज मंडल कहते हैं कि रामाश्रय जब कभी जमशेदपुर आये वीरेन्द्र साये की तरह उनके साथ रहा। सूरज के मुताबिक वीरेंद्र का एक-रिश्तेदार मगन बहादुर सिंह है जो जमशेदपुर का बड़ा ठेकेदार है। रामाश्रय सिंह के माध्यम से वीरेंद्र ने मगन बहादुर को कई बड़े लाभ दिलवाये। निर्मल महतो ने इस बात का भी कड़ा विरोध किया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और विधानसभा में मोर्चा के नेता शिबू सोरेन ने 'माया' को बताया कि 'वीरेंद्र सिंह सौ फीसदी रामाश्रय सिंह का पालतू गुण्डा है। निर्मल की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत हुई है। रामाश्रय इस बात को हरगिज नकार नहीं सकते कि सिंहभूम में वीरेंद्र उनका सिपहसालार है।'

दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक स्टीफेन मराण्डी कहते हैं, "सुवर्ण रेखा परियोजना में ठेकेदारी के सवाल पर भी विवाद इस हादसे की तह में है। निर्मल महतो हरदम बाहर के ठेकेदारों द्वारा इस परियोजना में काम करने का विरोध करते थे। पर रामाश्रय ने अपने लोगों को यहां ठेकेदारी में भर रखा है।"

विधायक स्टीफेन मरांडी का कहना है कि चांडिल के इलाके से गत विधान सभाई चुनाव में निर्मल खड़े हुए थे पर थोड़े मतों से हार गये थे। लिहाजा, सुवर्ण रेखा परियोजना का इलाका उनका प्रमुख कार्य-क्षेत्र था। रामाश्रय सिंह के पोषित ठेकेदारों का वह अरसे से यहां विरोध करते आ रहे थे। इसलिए स्टीफेन को संदेह है कि इस खूनी वाकये के पीछे सुवर्ण रेखा परियोजना की कोई रंजिश है।

रामाश्रय सिंह इन तमाम आरोपों के बावजूद खामोश हैं। रामाश्रय के चंद शुभचिंतकों का खयाल है कि इन आरोपों के पीछे इंका की राजनीति है। मुख्यमंत्री दुबे अभी भी रामाश्रय से कुढ़े रहते हैं। नतीजतन, रामाश्रय पर चढ़ बैठने के लिए मुख्यमंत्री मोर्चे के नेताओं की पीठ थपथपाते रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पांच सूत्री प्रस्ताव पारित किया है जिसमें प्रमुख मांग है कि रामाश्रय को सिंहभूम बीस सूत्री प्रभारी पद से अविलम्ब हटाया जाये।

उठते सवाल:

निर्मल की हत्या को लेकर कई और सवाल भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक खबर यह भी है कि हत्यारा वीरेंद्र सिंह निर्मल महतो, सूरज मंडल और ज्ञान रंजन से एक साथ कमरे में मिला। अचानक किसी बात को लेकर तनाव उभर गया। पर निर्मल ने यह कल्पना तक नहीं की थी कि वीरेंद्र के सिर पर खून सवार हो जायेगा। एक सवाल यह भी है कि हादसे की जगह मौजूद सुनील सिंह के पास जब रिवाल्वर था तो उसने हमलावरों पर गोली क्यों नहीं चलायी जब वे निर्मल को गोलियों से छलनी कर रहे थे। हत्यारों के दूर भागने के बाद क्यों फायर किया गया। क्या वह फायर महज दिखावा था। ज्ञानरंजन क्यों तब तक कमरे से निर्मल और सूरज का संदेश पाकर बाहर नहीं आये जब तक यह हादसा हो नहीं गया। पर यह सारे सवाल अनुत्तरित हैं। मुमकिन है कि ये सारे प्रसंग संयोगवश घटित हुए हों। हत्यारों की गाड़ी चलानेवाला अखिलेश सिंह पकड़ा गया, पर वह कुछ खास रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा है। वीरेंद्र सिंह और उनके दोनों भाई अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं।

पुरानी रंजिश ठेके को लेकर: स्टीफेन मरांडी

सूरज का इस्तीफा:

मोर्चा में सम्प्रति नौ विधायक हैं, पर इनमें भी कलह व्याप्त है। विधानसभा में मोर्चा के नेता शिबू सोरेन, उपनेता सूरज मंडल तथा सचेतक स्टीफेन मरांडी हैं। हाल में संपन्न विधानसभाई सत्र के बीच में ही अचानक सूरज मंड़ल ने उपनेता पद से त्याग-पत्र दे दिया। अपने इस्तीफे के बारे में, सूरज मंडल का कहना है, "मोर्चा के विधायकों ने मेरे आदेश की अवमानना की। मोर्चा की बैठक में यह तय किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मोर्चा के विधायक मतदान नहीं करेंगे इसके बावजूद विधायकों ने

मतदान किया। शिबू सोरेन उस समय बाहर थे। मुझे लगा कि उपनेता की बात जब कोई विधायक मानता ही नही, तो इस पद से इस्तीफा देना ही बेहतर है।" वह शिबू सोरेन से किसी मतभेद की बात का खंडन करते हैं। पर मोर्चे के एक दूसरे विधायक का कहना है कि शिबू सोरेन का सदन में मोर्चे का नेता होना सूरज को खलता है। सूरज को इस बात की शिकायत रहती है कि सिर्फ शिबू सोरेन की ही बातों को मोर्चा के विधायक क्यों अहमियत देते हैं। सदन के हाल के सत्र में स्थिति और गंभीर हो गयी। शिबू सोरेन इस सत्र में ज्यादातर अपने बीमार बेटे की चिकित्सा के चक्कर में दिल्ली में ही रहे। शिबू की अनुपस्थिति में उपनेता सूरज ही सदन में नेता की भूमिका निभाते रहे। पर कई मसलों पर सूरज का निर्देश मानने से मोर्चा के विधायकों ने इंकार कर दिया। नतीजतन, सूरज ने त्यागपत्र दे दिया। मोर्चा के एक विधायक कहते हैं कि सूरज की यह नाराजगी नयी नहीं। १९८० से १९८५ तक विधानसभा में झारखंड-मुक्ति-मोर्चा के नेता विनोद बिहारी महतो, उपनेता साईमन मरांडी और सचेतक सूरज मंडल रहे। विनोद बिहारी और साईमन चूंकि सदन में अधिक भाग नहीं ले पाते थे, इसलिए सचेतक सूरज मंडल पर ही मोर्चा का सारा दारोमदार रहता था। शिबू सोरेन उस समय दुमका से मोर्चा के सांसद थे, पर १९८५ के चुनाव में जब शिबू जामा विधानसभाई क्षेत्र में जीतकर आये, तो जाहिर था कि शिबू सोरेन की मौजूदगी में सूरज मंडल की अहमियत घट गयी। मोर्चे के सचेतक स्टीफेन मरांडी से भी सूरज के अंदरूनी सम्बन्ध मधुर नहीं हैं। ५ अगस्त को रांची में मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक खासतौर से सूरज मंडल के इस्तीफे पर विचार करने के लिए ही हुई थी, पर उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। उसके तीसरे दिन तो निर्मल महतो की हत्या ही हो गयी। सूरज के त्यागपत्र-प्रसंग पर शिबू सोरेन ने 'माया' को बताया, "इस विवाद का हल हम शीघ्र निकाल लेंगे। सूरज पुराने साथी हैं और उन्हें मना लिया जायेगा।" महेशपुर से मोर्चे के विधायक देवीधन बेसरा कहते हैं, "मोर्चे की ताकत किसी कीमत पर नहीं बिखरेगी। जो कुछ अंदरूनी मतभेद हैं, उन्हें शीघ्र सुलझा कर झारखंड आंदोलन को और तेज किया जायेगा।"

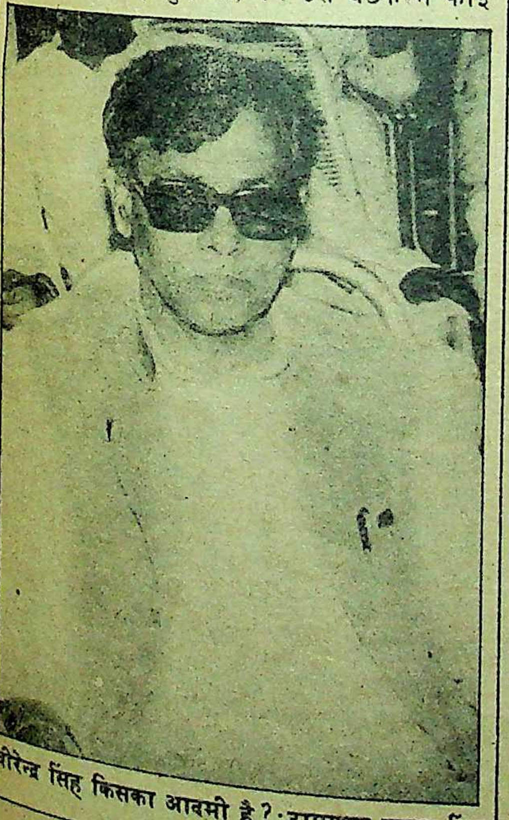

वीरेन्द्र सिंह किसका आदमी है?: रामाश्रय प्रसाद सिंह

डेविड का निलंबन:

४५ वर्षीय डेविड मूरमू शिकारीपाड़ा से मोर्चा के विधायक के रूप में चुनकर आये थे। वह उनका तीसरा टर्म था। पर विगत विधान परिषद् चुनाव के तत्काल बाद मोर्चा से विधायक डेविड को छह साल के लिए निलंबित कर दिया गया। डेविड कहते हैं कि मोर्चा के नेताओं के रवैये से बुरी तरह हताश हूं, अब वह मोर्चे में वापस लौटना भी नहीं चाहते। वह कहते हैं, "मोर्चे के लंबरदारों से मेरा मन उखड़ गया है।" आखिर महज नौ विधायकों की इस पार्टी से एक विधायक को खोने के पीछे क्या चक्कर है?

निलंबित: डेविड मूरमू

गांडे क्षेत्र से मोर्चा के विधायक और साथ ही मोर्चा के कोषाध्यक्ष सालखान सोरेन कहते हैं, "डेविड को गलत आचरण व अनुशासनहीनता के कारण निलंबित किया गया। न तो वह मोर्चा की किसी बैठक में भाग लेते थे न ही पार्टी लेवी तीन सौ रुपए मासिक जो विधायकों को देना पड़ता है, वही देते थे।" विधायक स्टीफेन मरांडी कहते हैं, "गत विधान परिषद् के चुनाव में मोर्चा के प्रत्याशी छत्रपति शाही मुंडा, जो मोर्चा के सचिव भी हैं, को मोर्चा का प्रत्याशी बनाया गया था। पर डेविड मूरमू ने छत्रपति को अपना मत न देकर पैसों के चक्कर में एक कांग्रेसी प्रत्याशी को दे दिया। इसीलिए, उन्हें निलंबित किया गया।"

बढ़ता मनमुटाव:

इसके अलावा 'आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन' के युवा कार्यकर्ताओं से भी मोर्चे के नेताओं का मनमुटाव बढ़ा है। स्टूडेंट यूनियन के नेता सूरज सिंह बेसरा से मोर्चा-नेताओं की अनबन कई बार प्रकाश में आयी। इसकी वजह है कि झारखंड स्टूडेंट यूनियन के युवा तर्कों का विद्रोही तेवर शुरू से ही समझौतावादी पटरी पर चलनेवाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को रास नहीं आया। इन्हीं सब कारणों से १९७१ से अब तक मोर्चा में कई बार फूट भी पड़ी। इसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो इन दिनों समानांतर झारखंड मुक्ति मोर्चा चला रहे हैं। विनोद खुद तो सिंदरी से विधायक हैं ही, उनके गुट में दो और विधायक हैं। धनबाद के पूर्व सांसद मजदूर नेता ए०के० राय की पहल से विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जैसे जुझारू आदिवासी नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम आदिवासियों के बीच लहराया। पर कभी झंडे के रंग के सवाल पर, कभी निजी स्वार्थ व अहम के टकराव को लेकर मोर्चा कई बार टूटा और नये-नये गुट बने। मोर्चा का नेतृत्व इस सवाल पर कभी स्पष्ट नहीं हो सका कि कांग्रेस के करीब आना उनके लिए उचित है या कांग्रेस का विरोध करना। इंका के पूर्व विधायक ज्ञानरंजन की भी पूरी राजनीति बस मोर्चा के इर्द-गिर्द ही रही। मोर्चे के नेताओं को कांग्रेस की गोद में बिठाने का काम ज्ञानरंजन ही करते रहे। अभी भी 'आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन' के युवा तुर्क और मोर्चा के नेताओं में यही मतभेद है कि मोर्चा का कांग्रेस से संबंध कैसा रहे।

झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ था तो आदिवासियों ने काफी उत्साह से मोर्चा का साथ दिया क्योंकि सिंहभूम से इंका सांसद बागुन सुम्ब्रई, खुंटी के इंका सांसद साइमन तिग्गा सरीखे कांग्रेसी आदिवासी नेताओं से सब परेशान थे। अरसे तक बागुन सुम्ब्रई ने झारखंड के नाम पर अपनी दूकानदारी चलायी फिर कांग्रेस में मिल गये। निरल एनेम होरो, जो तोरपा अनुसूचित जनजाति सुरक्षित क्षेत्र से विधायक हैं, अपनी झारखंड पार्टी अलग ही चलाते हैं। ऐसे में, मोर्चा के उदय से आदिवासियों में एक विश्वास जगा कि उनके लिए लड़नेवाला असली संगठन यही होगा। पर मोर्चा के विधायक व नेता जब खुद आपस में लड़ने लगे तो मोर्चे से भी आस्था उठती चली जा रही है। निर्मल महतो की हत्या ने मोर्चा को एक और झटका दिया है पर इसके आसार कम ही हैं कि मोर्चा के नेता आदिवासियों के सुलगते सवालों को लेकर कभी गंभीर होंगे।

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार, सुधांशु, रवि अटल

दहशत, दहशत और दहशत

पंजाब में जारी आतंकवाद का पंजाब के बाहर सर्वाधिक डरावना साया दिल्ली पर मंडरा रहा है। पुलिस की गश्त और रास्तों पर लकड़ी और लोहे की छड़ों के बाड़ों को देखकर ऐसा लगता है, जैसे अभी हमला होनेवाला है। इस आतंक ने पिछले तीन साल में राजधानी के स्वरूप में क्या परिवर्तन किया है, और यहां के निवासियों के जीवन तथा मानसिकता पर क्या प्रभाव डाला है?

आतंक फैलाने के लिए: गत ३० जुलाई को ३३० नंबर की बस विस्फोट के बाद।

पंजाब के बाद आतंकवादियों का देश में दूसरा अभयारण्य बन चुकी दिल्ली पर दहशत के काले बादल छाये हुए हैं। इस सदी में यहां न कभी ऐसी गर्मी पड़ी, न दहशत से कभी लोग ऐसे दुबके। १०-११ मई, १९८५ के ट्रांजिस्टर बम कांड ने दिल्ली में ४९ लोगों की जानें ली थीं। "इसके बावजूद दो घंटे में सब सामान्य हो गया"—पुलिस आयुक्त वेद मारवाह कहते हैं। पर इस बार तो आतंकवादियों ने आम जनजीवन में भारी अफरातफरी मचा दी है। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी। स्वतंत्रता की ४०वीं वर्षगांठ पर अम्बेदकर और शिवाजी स्टेडियम में करीब ४० हजार बच्चों द्वारा १४ अगस्त को सम्पन्न होने वाला भव्य कार्यक्रम भय की भेंट चढ़ गया।

दूसरी ओर, दिल्ली के डेढ़ सौ से ज्यादा तिराहे-चौराहों और महत्वपूर्ण मुकामों पर पुलिस के जवान मोर्चाबंदी को मजबूर हैं। हर जगह रेत की बोरियों के पीछे से झांकती पुलिस की बंदूकें आतंकवादियों का आखेट करना चाहती हैं। करीब इतनी ही जगह में रास्तों पर लोहे के बाड़े खड़े कर दिये गये हैं। यहां रात के अंधेरे को चीरने की कोशिश करती पुलिस की टार्चें हर आती-जाती गाड़ी में आतंकवादियों की टोह लेती हैं। रात-दिन पुलिस नियंत्रण कक्ष की २०० गाड़ियां शांति के लिए सरपट भागती रहती हैं। राजनीतिक धमकी-धमाकों, चेतावनी और चमचागिरी के पोस्टरों से पटी रहनेवाली राजधानी की दीवारों पर अब आतंकवादियों की तलाश के पोस्टर हैं।

बावजूद इनके दिल्ली की सड़कों से आतंकवादी अनजान नहीं। भूत की तरह आते और वारदात कर भाग जाते आतंकवादी आमफहम के दिमाग में इतना भय भर चुके हैं कि हर अफवाह सच लगने लगी है। स्कूलों में हाल के आतंक के पीछे आतंकवादियों से ज्यादा इन अफवाहों का योगदान रहा। रही-सही कसर खोजी पत्रकारों की खबरों ने पूरी कर दी। श्री मारवाह ने कहा— "किसी भी स्कूल ने आतंकवादियों की धमकी की इत्तला नहीं की है। यह सब अफवाह है।" पर पुलिस को भय का माहौल दूर करने के लिए स्कूलों के गेट पर पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा। आसपास सादी वर्दी में पुलिस वाले मंडेराने लगे

आम जनजीवन में अफरातफरी मचाने वाला दौर गत ७ अगस्त के अखबारों में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पी०टी०आई०) के हवाले से छपी खबर के कारण हुआ। खुफिया सूत्रों के हवाले से छपी इस खबर में बताया गया कि जाने-माने पब्लिक स्कूलों में आतंकवादियों के हमले की आशंका से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। कुछ स्कूलों के अधिकारियों को धमकी मिली है। अगले दिन सारे अखबारों में इस खबर की प्रतिक्रिया में होने वाली हलचलों की खबर थी। सभी स्कूल, शिक्षक और अभिभावक आतंक की लपेट में आ चुके थे। सभी अखबारों ने आला पुलिस अफसरों के हवाले से आतंकवादी हमले की आशंका को गलत बताया, पर आतंकवादी आतंक के अपने मकसद में कामयाब रहे।

आतंकवाद की शुरुआत: दिल्ली में छिटपुट आतंकवाद की शुरुआत तो १९८२ में श्याम नगर में जत्थेदार संतोख सिंह की हत्या के साथ ही हो चुकी थी। पर थोक आतंकवाद की पहली वारदात ८ से १३ मार्च १९८३ के बीच आनंद और स्वर्ण सिनेमा तथा अंतर-राज्यीय बस अड्डा और पालिका बाजार में बम विस्फोटों से हुई। इनमें पांच लोग मारे गये और ५० जख्मी हुए थे। ८ मार्च, १९८४ को दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरबस सिंह मनचंदा की हत्या हुई। इसके बाद कई बैंक डकैतियां पड़ीं। १०-११ मई, १९८५ को ट्रांजिस्टर बम कांड हुआ। ३१ जुलाई, १९८५ को नेशनल कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज और दिल्ली मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष तथा इंका सांसद ललित माकन और उनकी पत्नी तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल डा० शंकरदयाल शर्मा की बेटी गीतांजलि की हत्या हुई। ४ सितंबर, १९८५ को

संजय गांधी के साथी और इंका के महानगर पार्षद अर्जुन दास की हत्या हुई।

१९८६ के दौरान दिल्ली में आतंकवादी कोई बड़ी वारदात नहीं कर पाये, पर १९८७ दिल्ली के लिए मनहूस रहा। नवंबर, '८४ के दंगों के बाद पुलिस का कायाकल्प न होता, तो न जाने कितनी वारदातें होतीं। इन दंगों के बाद श्रीवास्तव कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियां ४४ से बढ़ाकर २०० कर दी गयीं। २०० से ज्यादा यमाहा और बुलेट मोटरसाइकिलें खरीदी गयीं। पांच हजार नये सिपाही भरती किये गये। १ उपायुक्त, २ सहायक उपायुक्तों, ८ इंस्पेक्टरों और २५ सबइंस्पेक्टरों को लेकर आतंकवादी निरोधक प्रकोष्ठ बनाया गया। इतनी चौकसी के बाद वारदातों में कुछ कमी अवश्य आयी।

आतंकवादियों ने १९८७ में जितनी बार हमले की कोशिश की, अगर उन्हें कामयाबी मिलती तो वे दिल्ली को सैकड़ों शवों से पाट देते। १५ अप्रैल को पुरानी दिल्ली और ३० जुलाई को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर उन्होंने भयानक बम रखे। अगर एक भी जगह विस्फोट होता तो कम-से-कम २५० लोग मौत के घाट उतरते। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्रम बम था। इसमें ११ मिनट का टाइमर था। जिस समय एक बेरोजगार अब्दुल्ला के बताने पर सब इंसपेक्टर जीवन सिह ड्रम के पास पहुंचे थे, १० मिनट हो चुके थे। सिर्फ एक मिनट में ही लगभग २५० जानें बचायी जा सकीं। इसी तरह नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में कुली इम्तियाज को एक लावारिस ब्रीफकेस मिला। वह उसे क्लाक रूम में ले गया। वहां सब-इंसपेक्टर बनवारीलाल और सुखमिंदर सिह ने बम निरोधक दस्ते को बुलाकर उसे खोला, तो उसमें टाइम बम निकला। इसमें १२.१५ बजे का टाइम फिक्स था। बहरहाल १२.१० पर बम बेकार किया गया। इससे भी कई जानें जाने से बच गयीं।

इस साल अभी तक आतंकवादी १६ लोगों की हत्याएं कर चुके हैं। कुछ-न-कुछ गड़बड़ करके वे अपनी मौजूदगी का अहसास कराते हुए राजधानीवासियों को आतंकित किए हुए हैं। ढाई महीने की ही बानगी देखिए :

२४ मई—रात ११ बजे जनकपुरी के मछली बाजार में स्कूटर पर सवार दो आतंकवादियों ने बम फेंका। इससे नौ लोग घायल हुए।

५ जून—पश्चिम बिहार में धार्मिक स्थल पर बम फेंका गया। इमारत को नुकसान पहुंचा। उस समय वहां कोई था नहीं, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। इसके दो दिन पहले ही आतंकवादी हमले की आशंका में पुलिस को चौकस किया गया था।

९ जून—ओखला के पास रेल पटरी पर बम मिला।

१० जून—गुरुद्वारा बंगला साहिब के बाहर बम मिला।

१२ जून—तुगलकाबाद और ओखला रेलवे स्टेशनों के बीच बम मिला।

१३ जून—आधे घंटे तक आतंकवादी ईस्ट आफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश भाग-१, अलकनंदा और तुगलकाबाद में गोलियां बरसाते रहे। १४ लोग मारे गये।

२५ जून—दो जगह गोलियां चलने के बाद रेड अलर्ट।

३० जून—बलजीत नगर में आतंकवादियों को पकड़ने गयी पुलिस पर हमला। एक कथित आतंकवादी पृथ्वीपाल सिह मरा। चार घायलों में दो पुलिसवाले भी थे।

३ जुलाई—मायापुरी में मोटर साइकिल पर सवार दो लोगों ने गोलियां चलाईं।

३० जुलाई—भाजपा के महानगर पार्षद और दक्षिण दिल्ली जिला इकाई के अध्यक्ष हंसराज सेठी की हत्या। भाजपा के ही नगर निगम पार्षद बलवंत राय मुंजाल की हत्या की कोशिश में उनका भाई सुदर्शन मुंजाल मारा गया। शाहदरा से केन्द्रीय सचिवालय जा रही ३३० नंबर की बस में विस्फोट।
नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ब्रीफकेस-बम मिला

१० अगस्त—त्रिनगर बस अड्डे से स्कूटर (डी०डी०आई०-८५०९) छीनकर भागने की कोशिश में जनता की मदद से दो आतंकवादी अमरजीत सिंह और हरजीत सिंह गिरफ्तार। भटिंडा के रहने वाले इन दो आतंकवादियों को इनके गिरोह ने लक्ष्य की जानकारी और हथियार तब तक नहीं दिये थे।

१२ अगस्त—मस्जिद मोठ से तीन आतंकवादी डी०एच०ई०-३२९४ फियट कार छीनकर फरार। पुलिस की घेराबंदी देखकर आतंकवादी आतंकवादियों के गढ़ गोविंदपुरी में कार छोड़कर फरार।

बेगुनाहों की हत्या: ग्रेटर कैलाश में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बहल परिवार।

निहत्थे लड़ें आतंकवाद से

दिल्ली में दहशत के शिकार नेताओं में पहले इंका के ही लोग ज्यादा थे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोगों को धमकी मिली थी, पर कभी किसी पर कातिलाना हमला नहीं हुआ। पहली बार ऐसा गत ३० जुलाई को हुआ। इसके बाद भाजपा के कई स्थानीय नेताओं को धुंआंधार धमकियां मिली हैं। इसी कारण प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने पुलिस आयुक्त वेद मारवाह को पत्र लिखकर अपने कार्यकर्ताओं को हथियारों के लाइसेंस उदारता से देने की मांग की, ताकि वे उग्रवादियों से मुकाबला कर सकें।

पर नवंबर, '८४ के दंगों के बाद से ही पुलिस ने जनसाधारण को हथियारों के लाइसेंस देने कम कर दिये हैं। सहायक पुलिस आयुक्त (लाइसेंस) जी सी द्विवेदी ने कहा, "हम सचमुच जीवन पर खतरा होने की स्थिति में लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर देते हैं।" पर अगर ऐसा होता तो रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस ज्यादा जारी किये जाते। उलटे पुलिस नवंबर, '८४ जैसी स्थिति की आशंका से ग्रसित है। एक तरफ सरकार और पुलिस चाहती है कि आतंकवादियों से जनता मुकाबला करे, दूसरी ओर वह जनता को हथियारबंद करने का जोखिम भी मोल नहीं लेना चाहती।

दिल्ली में १३ अगस्त, १९८७ को कुल ४६६०० लाइसेंसी हथियार थे। ये हथियार पुलिस और सुरक्षा बलों के अतिरिक्त हैं। इस दिन १३१२ अर्जियां विचाराधीन थीं।

वर्ष १९८५ में रिवाल्वर/पिस्तौल के ५३९, बंदूक के ६२२, राइफल के १०४, १९८६ में रिवाल्वर/पिस्तौल के ३९६, बंदूक के ८५६, राइफल के १२३ और १३ अगस्त १९८७ तक रिवाल्वर/पिस्तौल के १६८, बंदूक के ४७१ और राइफल के ९१ लाइसेंस दिये गये।

लोग व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस मांगते हैं। पर आंकड़े गवाह हैं कि पुलिस लोगों को दिन-प्रति-दिन ज्यादा निरुत्साहित कर रही है। पुलिस संस्थानों की सुरक्षा के लिए ज्यादा चिंतित है। इसीलिए बंदूकों और राइफलों के ज्यादा लाइसेंस ज्यादातर संस्थानों के लिए हैं। पुलिस खुद लोगों की हिफाजत में नाकाम है। जनता को अपनी हिफाजत के लिए हथियार नहीं दिये जा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में आतंकवादी वारदातों में अभी तक किसी आतंकवादी ने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है।

—कुमार गिरि

साक्षात्कार : वेद मारवाह,

पुलिस आयुक्त, दिल्ली

'पुलिस हाय-हाय' करने से आतंकवादी समस्या हल नहीं हो सकती

वेद मारवाह को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नवंबर, १९८४ के दंगों के बाद बनाया गया था। उस समय उन्हें कांटों भरी कुरसी मिली। एक तरफ दंगों के कारण सिखों की आहत भावनाएं, दूसरी ओर पुलिस विफलता पर धाराप्रवाह आलोचनाएं। इससे पुलिस का मनोबल भी ध्वस्त था। इसके बाद उन्होंने स्थिति को जिस ढंग से संभाला, उससे उनकी धाक जमी। इसी कारण जब पंजाब के पुलिस महानिदेशक पद से रिबेरो की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने की स्थिति में नये नामों की चर्चा हुई, उस फेहरिस्त में पहले नंबर पर थे वेद मारवाह। मिलनसार मारवाह से 'माया' की बेबाक बातचीत के अंश :

माया : स्कूली बच्चों का सामूहिक स्वतंत्रता दिवस समारोह क्यों रद्द किया गया?

मारवाह : हमसे इस बारे में कोई परामर्श नहीं किया गया। यदि करतें तो हम ऐसी कोई सलाह नहीं देते। उनसे (आतंकवादियों से) समस्या तो कहीं भी हो सकती है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बदल दें। यह तो उन्हीं के जाल में फंसना होगा।

माया : स्कूलों को मिलने वाली धमकियों और फिर होने वाली छुट्टी के बारे में बतायेंगे?

मारवाह : हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि किस स्कूल में कुछ (धमकी) आया है। यह सब अफवाह है। एक बार प्रेस ने यह सब छापना शुरू कर दिया, तो फिर अफवाहों का सिलसिला चल पड़ा। हमारे पास ऐसी एक भी शिकायत नहीं आयी है। पर इससे यह फायदा भी हुआ कि बच्चों की समझने की क्षमता पर असर पड़ा। हमें उम्मीद है कि पता चलने पर बच्चे हमें आतंकवादियों के बारे में बतायेंगे।

माया : पंजाब के बाद दिल्ली आतंकवादी समस्या का गढ़ बन गया है। क्या इसका ताल्लुक नवंबर, '८४ के दंगों से भी है?

मारवाह : दूसरा स्थान तो दिल्ली ही है, क्योंकि यहां उनको प्रचार मिलता है। जो प्रचार उन्हें पंजाब में दस घटनाओं से नहीं मिलता, वह दिल्ली में एक घटना से मिलता है। आतंकवादियों के दो लक्ष्य हैं। एक तो जनता में आतंक पैदा किया जाये। दूसरा सरकार को जनता के सामने कमजोर साबित किया जाये ताकि सरकार उनके दबाव में आ जाये। अगर उनके दबाव में हम आ गये तो उनका लक्ष्य पूरा होगा।

माया : तो क्या नवंबर, १९८४ के दंगा पीड़ितों में से कुछ आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं?

मारवाह : वास्तविक पीड़ितों की संख्या तो बहुत कम है। पर जब किसी को सिर्फ इसीलिए जान-माल का नुकसान पहुंचाया जाये कि वह किसी समुदाय विशेष का है तो उसका रोष पूरे समुदाय को होता है। इससे तो उनका विश्वास दिल्ली के समाज, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पुलिस के साथ कम हो जाता है। दिल्ली पुलिस के हिसाब से हमने यह विश्वास कायम करने की काफी कोशिश की है। मैं समझता हूं कि हम काफी सफल भी रहे हैं। अगर समस्या सिर्फ पीड़ितों की होती तो इतनी गंभीर नहीं होती।

माया. एक तरफ आप ज्यादा संगठित होने की बात करते हैं। इसके बावजूद दिल्ली में आतंकवाद बढ़ने की वजह?

मारवाह : मैं नहीं मानता कि दिल्ली में आतंकवाद बढ़ रहा है। १९८५ में ५०-६० हत्याएं हुईं। १९८६ में एक भी नहीं हुई। १९८७ में अभी तक १६ हुई हैं। मुझे यह कहने में फिर भी संकोच होता है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, जिसमें ऐसी वारदातों को बिलकुल रोका जा सके। ऐसा करना बहुत कठिन है। क्योंकि इनके लक्ष्य असीमित हैं। लक्ष्य दिल्ली का हर आदमी है। कोई खास लक्ष्य हो तो उसे रोका जा सकता है। दिल्ली का इलाका १५०० वर्ग किलोमीटर और सड़कें १६००० किलोमीटर हैं। दिल्ली की आबादी ८० लाख है। इतने बड़े शहर के कोने-कोने में निगरानी संभव नहीं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने क्षमता दिखायी है। ढाई साल में हुई हर आतंकवादी घटना में हमने अभियुक्तों को पकड़ा। यह संभव है कि कुछ अभियुक्त बाहर हों। पर हमने सौ फीसदी मामले हल किये हैं। (वे हर बड़े मामले में पकड़े गये आतंकवादियों का ब्यौरा देते हैं) सौ फीसदी मामले हल करना मामूली बात नहीं है। पर हम जनता से तारीफ की उम्मीद नहीं करते। क्योंकि जब तक ऐसे मामले होते रहेंगे जनता तारीफ नहीं कर सकती। चूंकि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, इसलिए वारदातें होने से रोकना कठिन है।

माया : जिन देशों में आतंकवाद की समस्या पुरानी है, वहां उनसे निबटने के तौर-तरीकों का कभी अध्ययन हुआ है?

मारवाह : ऐसा नहीं हुआ है। आप ऐसा कोई देश बताइए जहां आतंकवाद पर पूरी तरह काबू पाया गया हो। लंदन में घटनाएं होती हैं, रोम में होती हैं।

माया : क्या दिल्ली में आतंकवादियों को राजनैतिक संरक्षण भी है?

मारवाह : इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

माया : क्या दिल्ली पुलिस में आतंकवादियों की घुसपैठ है?

मारवाह : मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

माया : आतंकवादियों के बारे में आपकी भावी योजना?

मारवाह : इस समस्या का हमें मिलकर मुकाबला करना है। पुलिस को गाली देने से समस्या हल होने वाली नहीं। पुलिस और जनता एक तरफ है, एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन प्रेस ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि जहां कोई आतंकवादी घटना होती है, वहां कोई 'आतंकवादी हाय-हाय' तो करता नहीं, दिल्ली पुलिस हाय-हाय शुरू हो जाती है। दिल्ली पुलिस हाय-हाय करने से तो आतंकवादी समस्या हल नहीं हो सकती। अब इन घटनाओं के बाद प्रदर्शन और बंद आयोजित होते हैं। जिस पुलिस बल को आतंकवादियों को पकड़ने में भिड़ना चाहिए, उसे इनमें उलझ जाना पड़ता है। इससे तो आतंकवादियों को मदद मिलती है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं वे ऐसे जाल में नहीं फंसे। पुलिस की कमी को जरूर बतायें, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। कमी जरूर है। व्यक्तिगत कमी भी हो सकती है, हमारे संगठन की कमी भी हो सकती है। प्रेस और जनता से हम सहयोग भी लेंगे, उनकी आलोचना भी हम सुनेंगे। पर पुलिस को पत्थर मारने से या उसकी हाय-हाय करने से तो समस्या नहीं सुलझ सकती। दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा नहीं होता। अब उत्तरी आयरलैंड को ले लीजिए। १९७२ में मैं लंदन में था। उस साल वहां ५०० घटनाएं हुईं। कभी किसी ने पुलिस हाय-हाय नहीं की। बल्कि वे कहते हैं कि पुलिस को ज्यादा साधन दिए जायें। लेकिन, हमारे दिल्ली के नागरिकों को गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें प्रेस का बहुत बड़ा हाथ है?

माया : गुमराह करने में?

मारवाह : नहीं, गलत अपेक्षा जनता के दिमाग में भरने में।

—कुमारगिरि

आतंकवादी हमले से पहले गाड़ियां चुराते हैं। इसे देखते हुए कोई भी वाहन चोरी होते ही अब पुलिस सक्रिय हो जाती है। स्थानीय लोगों की सहानुभूति और समर्थन के बिना आतंकवादी कारगर नहीं हो सकते। नवंबर, ८४ के दंगों ने इन्हें कारगर होने के लिए ठोस आधार प्रदान किया। आज जिन इलाकों में दंगा पीड़ित जाकर बसे या समुदाय विशेष के लोगों का बाहुल्य है, वहीं आतंकवादियों की खोह बन गयी है। एक पुलिस अफसर ने 'माया' को बताया, "आपरेशन ब्ल्यू स्टार से ज्यादा आतंकवादी नवंबर,४ के दंगों से पैदा हुए।" दिल्ली पुलिस गोविंदपुरी, तिलकनगर, उत्तम नगर, नांगलोई और जनकपुरी को ऐसे ही इलाके मानती है। १३ जून और ३० जुलाई की वारदातों में शामिल आतंकवादियों में से तीन गोविंदपुरी बताये जाते हैं। इनमें से दो के मां-बाप आतंकवादियों को आश्रय देने के कारण पहले से ही जेल में हैं।

जनकपुरी के मछली बाजार में २४ मई को बम फेंकनेवाले तीन आतंकवादियों में से दो नांगलोई और एक तिलक नगर में २९ मई को गिरफ्तार किये गये थे। इनके पास से पांच देसी बम, दो देसी रिवाल्वर, आठ कारतूस, आंसू गैस का एक गोला और सिंगापुर का पासपोर्ट मिला था। आतंकवादी इकबाल सिंह, सतपाल सिंह और गुरविंदर सिंह में से गुरविंदर के पिता की नवंबर, '८४ के दंगों में हत्या हो गयी थी। १३ जून को १४ लोगों की हत्या करनेवाले गिरोह का परमजीत सिंह उर्फ खालसा उर्फ संकटा २५ जून को स्वर्ण मंदिर परिसर से व्यापक पुलिस तलाशी के दौरान पकड़ा गया था। गुरविंदर की तरह वह भी नवंबर, '८४ के दंगों का पीड़ित है। वह भी दिल्ली की ही गोविंदपुरी का रहने वाला है। उसके परिवार को भी दिल्ली छोड़कर पंजाब में बसना पड़ा था।

धमकियों का ही डर :दिल्ली में आतंकवादियों से लोगों के डर के पीछे वारदातों से ज्यादा धमकियों की धुकधुक है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार इन धमकियों की तादाद पांच हजार से भी ज्यादा हो सकती है। हर हफ्ते-दस दिन पर कहीं-न-कहीं बम होने की फर्जी धमकी फोन पर मिलती है। धड़ाधड़ इमारत खाली हो जाती है। ऐसा प्रायः उन इमारतों में किया जाता है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ मौजूद रहते हैं। अधिकांश धमकियां बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम से मिलती हैं। कई नामी आतंकवादियों को दबोचनेवाले अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आमोद कंठ कहते हैं, "९५ फीसदी धमकियां झूठी होती हैं। इन्हें दफ्तर के लोग, पड़ोसी, संबंधी आदि तमाशा बनाने या दुश्मनी निकालने के लिए देते है।" पुलिस भले ही डाक चिन्ह, लिफाफा, मजमून, भाषा, लिखावट आदि के जरिए धमकी झूठी होने का भरोसा कर बैठती है लेकिन लोगों का तो भय बना ही रहता है। खासकर यह देखते हुए कि पुलिस फर्जी धमकी भेजने वाले या फोन करने वाले किसी को भी आज तक नहीं पकड़ पायी है।

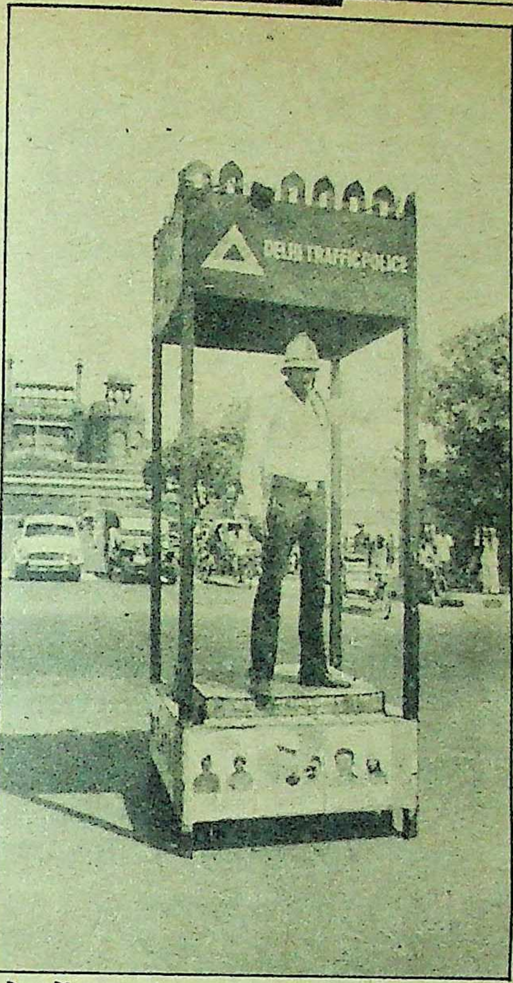

पोस्टरों का आतंक

धमकियों की छानबीन के बाद पुलिस जरूरी समझने पर लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा का इंतजाम भी करती है। महत्वपूर्ण नेताओं के अलावा राजधानी में करीब साढ़े तीन सौ लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा इसी कारण हो रही है। आतंकवादी वारदातों की छानबीन के मामले में दिल्ली पुलिस का सौ फीसदी सफलता का दावा भले ही सच हो लेकिन वह दिल्ली को अभी निरापद नहीं बना पायी है। खासकर, पूर्व चेतावनियों के बावजूद कई बार वारदातें हुई हैं। १३ जून को आतंकवादी दिल्ली के सात किलोमीटर इलाके में आधे घंटे तक गोलियां बरसाते रहे। लेकिन, पुलिस किसी आतंकवादी को नहीं पकड़ पायी। डेढ़ सौ पुलिस पोस्ट हर बार बेकार साबित हुए हैं। २०० गाड़ियों और २०० मोटर साइकिलों की पेट्रोलिंग वारदातों के समय पेट्रोल बर्बाद करने वाली ही साबित हुई। हर बार यह जरूर हुआ है कि वारदात में इस्तेमाल वाहन घटना के कुछ घंटों में पुलिस ने बरामद कर लिये।

रो रही है हमारी पुलिस : गश्ती गाड़ियों में बैठे पुलिस वालों में से रात में कई तो दारू के नशे में बेकसूरों पर दनदनाते नजर आयेंगे। पुलिस की आलोचना पर आंखें टेढ़ी करने वाले पुलिस आयुक्त ने शायद ही कभी इनकी खोजखबर ली हो। १३ जून की वारदात के बाद बोट क्लब पर रात के समय पुलिस अकसर कुल्फीवालों से माल ऐंठती नजर आती है। दिल्ली पुलिस के आतंकवादी निरोधक प्रकोष्ठ में 'सिख' नाम से भी एक महकमा है। पुलिस आयुक्त वेद मारवाह ऐसे किसी महकमे से इंकार करते हैं। पर महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्ट्री में सहायक पुलिस आयुक्त सिख पदनाम से टेलीफोन नंबर—३३१२५३४ है। खुफिया एजेंसियों की तरह इस प्रकोष्ठ की गतिविधियां भी खुफिया बतायी जाती हैं। फिर भी श्री मारवाह की इस बात में दम है कि वे सिखों के मन में पुलिस का भरोसा कुछ हद तक कायम कर पाये हैं। आतंकवादियों की किसी भी बड़ी वारदात के बाद भी सिख आम दिनों की तरह सड़क पर नजर आते हैं।

दामन पर दाग : खुफिया एजेंसियों की विफलता के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही केन्द्र के दामन पर भी दाग है। इसी कारण ९ जुलाई को गृहमंत्री बूटा सिंह की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में लालकृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते और रामधन ने जबर्दस्त धुलाई की थी। १२ जून को कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग में एक सिख ने बताया था कि १७ जून को हरियाणा चुनाव से पहले दिल्ली और हरियाणा में आतंकवादी बड़ी वारदात कर सकते हैं। पर १२ जून का यह तार १५ जून को सरकार की नजरों में तब आया, जब १३ जून को दक्षिण दिल्ली में १४ लोगों की हत्या हो गयी। रामधन ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग भी की। पर सरकार की लाचारी बूटा सिंह की इस टिप्पणी से उजागर है—"यदि तार समय पर मिल भी जाता, तब भी शायद कुछ नहीं हो पाता।"

राजधानी में ११ जुलाई को पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उ०प्र०, म०प्र०, चंडीगढ़ और दिल्ली के आला सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों की बैठक हुई। मंत्रिमंडल सचिव बी०जी० देशमुख ने उसकी अध्यक्षता की। तय हुआ कि इन सभी जगहों पर आतंकवादी निरोधक प्रकोष्ठ बनाए जायें और सूचनाओं का आदान-प्रदान हो। पर दिल्ली में तो आतंकवादी निरोधक प्रकोष्ठ अरसे से हैं। बावजूद इसके आतंकवादी भी सक्रिय हैं और आतंक भी।

राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगते रहे हैं। कमलाकांत तिवारी ने तो तत्कालीन राष्ट्रपति कमलाकांत तिवारी ने तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पर भी ऐसा ही आरोप लगा दिया था। इसी कारण ज्ञानीजी के दबाव में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी करनी पड़ी थी। इंका के भी कई सिख नेताओं पर विरोधी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। पर अभी तक पुलिस ने अपना रुख राजनीतिकों की तरफ नहीं किया। पुलिस आयुक्त वेद मारवाह जब कहते हैं कि वे राजनीतिकों के संरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि राजनीतिकों का संरक्षण तो है, लेकिन उनकी नौकरी का सवाल भी है, जुबान कैसे खोलें?

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

—कुमार गिरि

दिल्ली में सक्रिय आतंकवादी :

पहले मामा, अब भांजे

राजधानी की आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र हरजिंदर सिंह ज़िंदा रहा है। १९८४ में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में डाका डालने तथा ३१ जुलाई, १९८५ को ललित माकन दंपति तथा ४ सितंबर, १९८५ को अर्जुन दास की हत्या में उसी का हाथ था। उसे जनवरी १९८६ में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार भी कर लिया था। बाद में वह गुजरात से भाग गया।

हाल में १३ जून और ३० जुलाई को हुई वारदातों में जिंदा के दो भांजे सुरजीत सिंह उर्फ पैंटा और परमजीत सिंह उर्फ काला का हाथ है। इन दोनों की मां और जिंदा की चचेरी बहन मोहिंदर कौर अपने पति स्वर्ण सिंह के साथ १९८५ से ही जेल में हैं। उन पर गोविंदपुरी के अपने घर में जिंदा को पनाह देने का आरोप है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पैंटा स्कूल छोड़कर चोरी और उचक्कागिरी करने लगा। इसके पहले उसने खालसा स्कूल से ग्यारहवीं की परीक्षा में ७० फीसदी नंबर हासिल किए थे। वह ८०० मीटर की दौड़ में दिल्ली का जूनियर चैंपियन था छोटी-मोटी वारदात करने वाला पैंटा अब १६ हत्याएं कर दिल्ली पुलिस का सबसे वांछित आतंकवादी बन चुका है। उसका छोटा भाई काला सातवीं पास है और वह पंजा साहिब ट्रांसपोर्ट में खलासी था। ८ जून से ही वह घर में ताला मारकर फरार हो गया था। उसका पिता स्वर्ण सिंह भी इसी ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर था। पुलिस ने काला का एक युवती के कंधे पर हाथ रखे फोटो भी बरामद किया।

आजकल पुलिस पंजाब की इस युवती की तलाश में है। इन दोनों को भागने में मदद करने वाले जसवंत सिंह और हीरा सिंह भी इसी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। पहली वारदात के हत्यारों में एक और परमजीत उर्फ खालसा उर्फ सकतार था, जो अमृतसर में पकड़ा गया। इनका संबंध भिंडरावाले टाइगर्स फोर्स से है। इस गिरोह के सरगना गुरबचन सिंह मनोचहल उर्फ बाबा और स्वर्ग जीत सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह हैं। मनोचहल पंथिक कमेटी का सदस्य है।

विस्फोटों में बब्बर खालसा माहिर है। राजधानी में जहां कहीं भी बड़े विस्फोटक और बम मिले हैं, उनके पीछे आतंकवादियों का यही गुट था। इसी गुट ने ट्रांजिस्टर बम कांड किया था। इसमें दिल्ली (४९), उ०प्र०, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-काश्मीर में ८५ लोग मारे गये थे। मुख्य अभियुक्तों में से करतार सिंह नारंग, मोहिंदर सिंह ओबराय और मोहिंदर सिंह खालसा सहित ६५ लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस चालान पेश कर चुकी है। पर बम कांड की योजना बनाने वाला करम सिंह कोहली उर्फ अनोख सिंह दिसंबर १९८६ में लुधियाना में गिरफ्तार होने के बावजूद वहीं से १२ फरवरी, १९८७ को पुलिस हिरासत से भाग निकला। वह कचहरी से पेशी के दौरान भागा। इसी दिन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने लुधियाना में ही पंजाब नेशनल बैंक से ५.६८ करोड़ रुपए लूटे थे। पर अनोख सिंह को भगाया बब्बर खालसा गुट के उसके सहयोगियों ने।

जिंदा खुद खालिस्तानी कमांडो फोर्स में रहा है। उसका सरगना सुखदेव सिंह उर्फ लाभ सिंह उर्फ सुक्खा सिपाही है। इसे भी पुणे में गिरफ्तार किया गया था, पर वह भाग निकला। इसी गिरोह का मथुरा सिंह अमृतसर के लोले गांव में पुलिस और सीआरपी से मुठभेड़ में मारा गया। गुरदेव सिंह इसी तरह ३ जुलाई को जालंधर जिले के अद्दतापुर में मारा गया। इस गिरोह के रणजीत सिंह कुक्की और सुखमिंदर सिंह सुखी अमेरिका में गिरफ्तार हैं। संत लोंगोवाल का हत्यारा जनरैल सिंह भी खालिस्तानी कमांडो फोर्स से संबद्ध था। वह भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने ही हरबंस सिंह मनचंदा, ललित माकन, अर्जुन दास, इंका सांसद वी०एन० तिवारी (चंडीगढ़), पंजाब केसरी के संपादक-रमेश चन्द्र और इंस्पेक्टर धन सिंह की हत्या की थी।

> कई आतंकवादियों के मारे जाने और गिरफ्तारी के बावजूद आतंकवादियों की ताकत कम नहीं हुई है। सुरजीत और परमजीत जैसे लोग इनसे जुड़ते रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यहां कितने आतंकवादी हैं।

इस गुट की शुरूआत जरनैल सिंह भिंडरावाले के बांए हाथ विरसा सिंह वल्टोहा ने की थी। शुरू से गुरिंदर सिंह भोला (मारा गया) और हरविंदर सिंह संधू इसमें रहे। वल्टोहा और संधू जोधपुर जेल में हैं। इन्हें आपरेशन ब्ल्यू स्टार के समय स्वर्ण मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। वल्टोहा के पास माउजर पिस्तौल थी। मनचंदा से लेकर धन सिंह की हत्या में इसी का इस्तेमाल हुआ था। स्वर्ण मंदिर में पुलिस कार्रवाई के पहले यह पिस्तौल सुक्खा सिपाही के पास पहुंच गयी थी। पुलिस को माउजर के वल्टोहा के पास होने की जानकारी थी। जोधपुर जेल में वल्टोहा से पूछताछ में इन हत्याओं का राज खुला। बाद में सुक्खा सिपाही को जब पुणे में गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से यह माउजर बरामद हुआ।

खालिस्तान कमांडो फोर्स के कुक्की और सुक्खी पर जनरल वैद्य की हत्या का आरोप है। इन्हें अमेरिका भागने में फर्जी पासपोर्ट आदि बनाकर देने वाले रणजीत सिंह, दर्शन सिंह, बलदेव सिंह और यशपाल कश्यप गिरफ्तार होकर जेल में हैं। अमेरिका में गिरफ्तार सुक्खी और कुक्की को भारत लाने के लिए सरकारी स्तर पर बातचीत जारी है।

दिल्ली की पहली बड़ी आतंकवादी वारदात-ज्ञानंद और स्वर्ण सिनेमा में बम विस्फोट से सुखवीर सिंह खालसा ने ८ मार्च को की थी। वह साल के अंत में पकड़ा भी गया। लेकिन, सबूत के अभाव में छूट गया। उसका संबंध आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन से था। वह खालसा कालेज, करोलबाग का पढ़ा था। इसके बाद दिल्ली में बिल्लू-बावला गैंग का आतंक रहा। १९८४ में इसी गैंग ने करोल बाग में माया ज्वेलर्स से ६ लाख रुपए का सोना लूटा था। इसी साल संसद मार्ग पर बैंक के बाहर इन्होंने एक बैंक कर्मचारी से नकद राशि छीन ली थी। ये एक स्कूटर पर भागे। पर बंगाली मार्केट और टालस्टाय मार्ग पर बने फ्लाईओवर के पास ये पकड़े गये।

हालांकि आतंकवादी गुटों में बंटे हुए हैं, लेकिन कई बार ये एक गुट से दूसरे गुट में चले जाते हैं। कई आतंकवादियों के मारे जाने और गिरफ्तारी के बावजूद आतंकवादियों की ताकत कम नहीं हुई है। सुरजीत और परमजीत जैसे लोग इनसे जुड़ते रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यहां कितने आतंकवादी हैं। पुलिस आयुक्त वेद मारवाह का मानना है कि आतंकवादी पंजाब से आते हैं, फिर वारदात कर वहीं वापस लौट जाते हैं।

—कुमारगिरि

बिल्किस बेगम हत्याकांड

पुलिसिया चेहरा

सच की तलाश : दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बिल्किस बेगम (इनसेट) का शव कब्र से निकाला गया

नागपुर की सी०आई०डी० पुलिस ने 'बिल्किस हत्याकांड' के अभियुक्तों को दस महीने बाद गिरफ्तार करके जन आंदोलन भले ही रुकवा दिया हो, मगर हत्याकांड की जांच में हुई लेट लतीफी से महाराष्ट्र पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिह्न लग गया है। जिस पुलिस की तुलना 'स्काटलैंड यार्ड' से की जाती हो और अन्य प्रदेश की सरकारें जिससे अपनी पुलिस को प्रशिक्षण दिलवाती हों वही यदि तमाम सबूतों और चश्मदीद गवाहों के होने के बावजूद हत्या को आत्महत्या माने, पुलिसिया पैंतरे से गवाह से गवाही बदलने के लिए दवाव डाले और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में दस महीने लगाये तो उसकी काबिलियत पर शक होना स्वाभाविक है। वह भी नागपुर की समाजसेवी संस्था 'घंटानाद' और इंका युवक संघर्ष समिति द्वारा घटना की जांच के लिए जन आंदोलन छेड़ देने के कारण ऐसा हो सका, अन्यथा पुलिस ने आत्महत्या का मामला कहकर इस हत्याकांड को दबाने की पुरजोर कोशिश की थी।

बिल्किस हत्याकांड : पिछले साल ७ अक्तूबर को नागपुर में मोमिन जुलाहों की घनी बस्ती में एक युवा गृहिणी की उसके मकान मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन सबों ने गृहिणी की लाश के साथ बलात्कार करके जला दिया। घटना इस प्रकार घटी :

घटना के दिन संतरा व्यापारी मोहम्मद रफीक सुबह अपनी बेटी निकी उर्फ यास्मीन (साढ़े तीन साल) को दोसर वैश्य भवन स्थित कान्वेंट स्कूल में छोड़ने के बाद संतरा मार्केट के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे ध्यान आया कि रुपए का बंडल वह घर में ही भूल आया है। जब रुपए लेने वह घर पहुंचा, तो स्नानागार में उसे अपनी बीवी बिल्किस बेगम की अधजली तथा अर्धनग्न लाश पड़ी मिली। रफीक ने अपने मकान मालिक रसूल पहलवान से संपर्क किया। रसूल अपने तीन साथियों (जलील चुकेवाले, कालिया मजीर तथा मो० इशाक) के साथ उनके मकान पर पहुंचा। शव को लेकर ये लोग मेयो अस्पताल गये, जहां दो डाक्टरों (डा० ए०एस० देउरकर एवं डा० चौधरी) ने शव परीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने मौत का कारण जलना बतलाया। पुलिस ने भी इसे आत्महत्या का केस मानकर फाइल बंद कर दी।

हत्या के रहस्य का परदाफाश कुछ दिनों बाद बिल्किस बेगम के यहां एक महीने पहले तक नौकरानी का काम करने वाली १३ वर्षीया शहनाज के बयान से हुआ। शहनाज ने अपनी एक सहेली से इस हत्याकांड के अपनी आंखों के सामने घटने की बात कही। मना करने के बावजूद उस सहेली ने यह बात फैला दी। चर्चा सुनकर मोहम्मद रफीक अपने साले सैयद मुमताज अली के साथ शहनाज से मिले। शहनाज ने उन्हें बताया कि सारी रात गुलाम रसूल के यहां वीडियो पर फिल्में देखने और सुबह का काम निपटाने के बाद जब वह बिल्किस के घर पहुंची, तो उसने गुलाम रसूल और उसके साथियों को बिल्किस के साथ मारपीट करते देखा। वे बिल्किस से 'सेफ' की चाभी मांग रहे थे। इसके बाद उन्होंने गला घोंटकर बिल्किस की हत्या कर दी। बाद में सबने उसके शव के साथ बलात्कार किया और फिर केरोसिन का तेल तथा एसिड छिड़ककर आग लगा दी। बाद में एक साथी कालिया मजीर जब तिजोरी खोल रहा था, तो उसकी नजर शहनाज पर पड़ी। उसने शहनाज को धमकी दी कि यदि उसने किसी से इस घटना का जिक्र किया तो उसका भीं वही हाल करेंगे जो बिल्किस का किया था।

शहनाज ने इस बीच बिल्किस के भाई और एक रिश्तेदार को सूचना देने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुई। इस बीच कालिया मजीर ने उसे दोबारा धमकी दी, जिससे उसने चुप्पी साध ली। बिल्किस के भाई सैयद मुमताज अली ने पुलिस को घर बुलाकर शहनाज से मिलवाया। शहनाज का बयान टेप कर लिया गया। शहनाज को पुलिस ने दूसरे दिन फिर से थाने बुलवाया। शहनाज के अनुसार पुलिस स्टेशन पर उसे एक महिला कांस्टेबल ने मारा और फिर तीन इंस्पेक्टरों ने धमकाकर एक सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लिये। दस दिन तक जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मुमताज अली ने पूछताछ की। पुलिसवालों ने उसे बताया कि शहनाज ने अपना बयान बदल दिया है। इस बीच मुजरिमों द्वारा पुनः धमकाये जाने पर शहनाज ने मोहल्ला बदल लिया। मोहम्मद रफीक ने शहनाज को तलाश कर १४ नवंबर को पुलिस उपायुक्त के सामने पेश किया, जहां एकांत में उसका बयान लिया गया। लेकिन इस सबके बावजूद जब कई दिनों तक कोई कार्यवाही होती नहीं दिखायी पड़ी, तो उन्होंने स्थानीय संस्था 'घंटानाद' और इंका युवा संघर्ष समिनि से मुलाकात की।

पुलिस की संदिग्ध भूमिका : इस केस में पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदेहास्पद रही। बिल्किस की मौत की सूचना पाते ही उसी मुहल्ले में रहनेवाला गुप्ता नामक एक युवक जब सूचना देने के लिए मोमिनपुरा पुलिस चौकी पहुंचा, तो वहां कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वहां से भाग कर जब दूसरी पुलिस चौकी पहुंचा तो थाने में सिर्फ एक सिपाही मौजूद था। उसने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

बिल्किस की हत्या के बाद उसके परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या से संबंधित तमाम सबूत एवं गवाहियां देने के बावजूद हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया। ३ नवंबर को शहनाज को तहसील पुलिस थाने बुलाकर न केवल दोपहर से शाम

तक रोके रखा गया, बल्कि एक 'बड़े' पुलिस अफसर के संकेत पर एक महिला कांस्टेबल ने उसे मारा और यह बयान देने के लिए मजबूर किया कि उसका पहला बयान गलत था और उसने ऐसी कोई घटना अपनी आंखों से नहीं देखी।

बिल्किस के पति मोहम्मद रफीक ने 'माया' को बतलाया, ''मैं घटना के दिन सिर्फ ३५ मिनट के लिए घर से बाहर रहा, इतनी ही देर में इतना बड़ा कांड घट गया! मामले की सूचना पाने पर भी पुलिस ने न तो घटना स्थल पर पहुंच कर कोई पंचनामा किया और न ही नियमानुसार पुलिस फोटोग्राफर से बिल्किस की लाश तथा घटनास्थल के चित्र खिचवाये, जबकि मामूली घटनाओं में भी पुलिस चित्र अवश्य खिचवाती है। पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब बिल्किस का सारा शरीर जल गया था, तो पहना हुआ अंडरवीयर एवं दरवाजे पर लगे साटन के परदे कैसे बचे रह गये जबकि परदे बिल्किस के पैर से सटे हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल से न तो मिट्टी का तेल व एसिड की बोतलें बरामद की और न बिल्किस की ब्रा, मैक्सी एवं पेटीकोट बरामद करने या उसे तलाशने की ऐहतियात ही बरती, जबकि सुबह बिल्किस ने यही ड्रेस पहनी हुई थी। पुलिस ने यह जानने की कतई कोशिश नहीं की कि ये पहने हुए कपड़े आखिर गये कहां? अगर वह इसे आत्महत्या का ही केस मानती थी, तो उसे इन बातों पर पूरी तरह से गौर करना चाहिए था। घटना स्थल पर एक अंगोछा व दुपट्टा मिला था जो न तो मेरा था और न ही बिल्किस का। तो फिर किसका था? उसे हमने पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन उसका क्या हुआ हमें आज तक पता नहीं।''

बिल्किस के हत्यारों को
गिरफ्तार करो
भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को
निलम्बित करो
विश्वास
जय युवक क्रांति दल
ROLLO

बिल्किस हत्याकांड की जांच के लिए धरना

बिल्किस के बड़े भाई ए०बी० सैयद भांडुप (बंबई) में रहते हैं। बिल्किस की मौत के बाद हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए उन्होंने अपना सारा कामकाज छोड़कर बंबई-नागपुर एक कर दिया था। उन्होंने 'माया' को बतलाया, ''जब मोमिनपुरा कब्रिस्तान में बिल्किस को दफनाने के लिए ले गये, तो मैंने उसका अंतिम दर्शन करने के लिए उसका चेहरा एकांत में देखने की दरख्वास्त की तो मैयत में गये सभी लोग वहां से हट गये। बिल्किस का चेहरा देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिंदा जल जाये तो उसके चेहरे और पूरे शरीर पर तमाम फफोले पड़ जाते हैं, लेकिन बिल्किस के चेहरे पर कोई फफोला नहीं था। उसके बाल एकदम काले थे, लेकिन वे हरे हो गये थे और औरतों ने जब मैयत में ले जाने के पूर्व उसे नहलाया तो बाल सिर से अलग हो गये थे। इन दोनों बातों ने उसी समय मेरे दिल में संदेह पैदा किया। एक संदेह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर भी हुआ। जीवित व्यक्ति के जलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्बन के चिह्न दिखने चाहिए थे, परंतु बिल्किस के शव-परीक्षण की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बिल्किस के शव को खुद हत्यारे टैक्सी में लादकर मेयो अस्पताल ले गये, साथ में परिवार का सदस्य न रहने पर भी वहां के डाक्टरों एवं वहां मौजूद पुलिस ने उनसे तत्काल कोई पूछताछ नहीं की। फिर केंद्रीय सरकार का नियम है कि यदि किसी विवाहित महिला की, विवाह के दस वर्ष के भीतर रहस्यमय ढंग से मौत हो जाये, तो उसकी तहकीकात भारतीय दंड विधान धारा ३०२ के अंतर्गत करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इसका भी पालन नहीं किया। इन सब बातों ने मेरे इस संदेह को पुख्ता कर दिया कि बिल्किस की मौत जलने से या हादसावश नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गयी है। पुलिस जिस तरह से मामले को टाल रही थी और पोस्टमार्टम करनेवाले डाक्टरों के व्यवहार ने मामला और भी संदेहास्पद बना दिया। फिर हमने भी ठान ली कि चाहे जो कुछ हो जाये मुजरिमों को कानून की हद तक पहुंचा कर ही रहेंगे।''

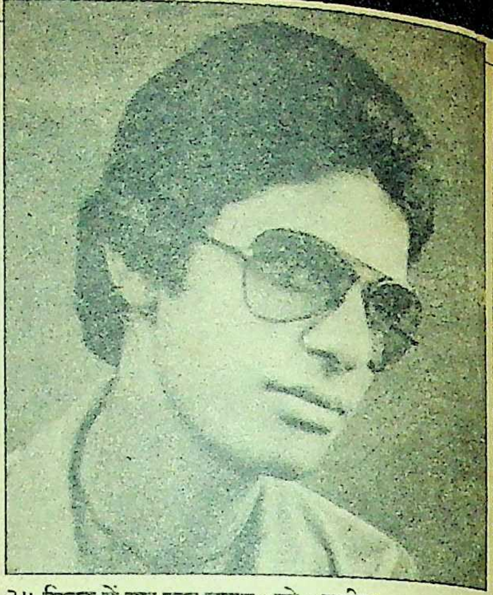

३५ मिनट में सब कुछ खतम : मो० रफीक

जन आंदोलन : 'घंटानाद' और 'इंका युवा संघर्ष समिति' ने मामले की सी०आई०डी० जांच कराने के लिए काफी प्रयास किये, मगर जब सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। दोनों संस्थाओं ने शहर के विभिन्न भागों में तीन दर्जन से भी अधिक सभायें आयोजित की, जिनमें शहनाज के बयान के टेप भी सुनवाये गये। इसके अलावा इन संस्थाओं ने पुलिस के पक्षपात पूर्ण रवैये के खिलाफ जुलूस भी निकाले। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया तो, मगर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब संघर्ष तेज करने की धमकी दी गयी, तो अंततः सी०आई०डी० जांच बैठा दी गयी।

उप पुलिस अधीक्षक जी०ज़ी० काडु (सी० आई०डी०) के नेतृत्व में जांच कार्य शुरू हुआ। ५ मार्च, १९८७ को बिल्किस का शव कब्र से निकाल कर पुनः शव परीक्षा के लिए भेजा गया। इसके अलावा सी०आई०डी० दल अन्य सबूतों की खोज में जुट गया। अंततः १५ जुलाई, १९८७ को सी० आई०डी० पुलिस ने मकान मालिक गुलाम रसूल हाजी मोहम्मद उर्फ रसूल पहलवान, उनकी बीवी जमीना बी, पुत्र रियाज अहमद, पड़ोसी तहसीन अर्सी, अब्दुल मजीर शेखचांद और अब्दुल जलील अनीमुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इतना सब करके उसने कोई तीर नहीं मारा है, क्योंकि इन अभियुक्तों के नाम घटना के तुरंत बाद से ही लिये जा रहे थे। सबूत भी इतने थे कि उनके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। मगर पहले पुलिस ने लेटलतीफी की और फिर सी०आई०डी० ने।

—बम्बई ब्यूरो और उमेश चौबे

असंतोष की आग : विश्वविद्यालय पुनर्गठन अध्यादेश के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला जलाते राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी

छाया : गोपाल संग

राजस्थान विश्वविद्यालय

फिर एक उफान

राजस्थान में विश्वविद्यालयों के स्वरूप और संख्या को लेकर शिक्षा जगत में बावेला मचा हुआ है। जो लोग विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे, यह मांग मंजूर कर लेने के बाद आंदोलनरत क्यों हैं ? राजस्थान में उच्चतर शिक्षा की दशा और दिशा को परख रहे हैं

ओम सैनी :

पांच अगस्त की सुबह राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागृह के बाहर प्रदेश के राजनीतिक दलों की युवा शाखाओं के संचालक और छात्र संगठनों के उत्तेजित नेता खड़े थे। कारण था, राजस्थान के मौजूदा तीन विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि। इसी प्रश्न पर विचार करने और आन्दोलन की रूपरेखा बनाने के लिए वे सभागृह का उपयोग करना चाहते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब इस काम के लिए सभागृह का ताला खोलने से मना कर दिया, तो नेताओं के सहयोगियों ने ताला तोड़ कर सभा की।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले पन्द्रह वर्ष से राज्य के छात्र एवं शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए नया संभागीय विश्वविद्यालय खोलनें की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इस मांग के औचित्य को समझती रही है और अब जबकि मौजूदा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जोधपुर वं उदयपुर के अतिरिक्त कोटा, बीकानेर तथा अजमेर विश्वविद्यालय इसी सत्र से प्रारंभ करने के अध्यादेश जारी हुए, तो छात्रों एवं शिक्षकों ने इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। मानविकी सभागृह में सभा के बाद राजस्थान छात्र युवा संघर्ष समिति के नाम से एक बयान जारी किया गया। इस बयान पर भाजपा, जनता, लोकदल, भाकपा व माकपा के छात्र सदस्य एवं युवा संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों व महामंत्रियों के हस्ताक्षर थे। बयान में विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन संभागीय आधार प करने व छात्रसंघों के चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदेश भर की शिक्षण संस्थाओं में तेरह अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसल दर्ज था।

आरोप : छात्र एवं युवा नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय को नय विश्वविद्यालयों के गठन के नाम पर काट क बौना बनाया है। मसलन राजस्थान विश्वविद्यालय को मात्र विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित ३३ विभाग एवं जयपुर स्थित चार संघटक महाविद्यालयों व दो इंजीनियरिंग कालेजों तथा मेडिकल औ आयुर्वेद संकाय तक सीमित कर आवासीय विश्व विद्यालय बना दिया गया है। इसके विपरीत नवगठित अजमेर विश्वविद्यालय को केवल सम्बद्धत (एफिलिएटेड) देनेवाला, तो कोटा को खुले विश्वविद्यालय का नाम देकर पत्राचार संस्था और बीकानेर विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया है।

उधर राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महा विद्यालय शिक्षक संघ की विभिन्न प्रादेशिक इका इयों ने भी राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्ब

कालेजों को अजमेर विश्वविद्यालय से जोड़े जाने का विरोध-पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को पेश किया है। इनका आरोप है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को शैक्षिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने के नाम पर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में नाजायज हस्तक्षेप किया है। इनके अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय उस वक्त तक आवासीय हो ही नहीं सकता, जब तक उसके साथ प्रदेश के दूरदराज के मेडिकल, इंजीनियरिंग व आयुर्वेद कालेज जुड़े हुए हैं। इस विरोध-पत्र में विशेष रूप से उन महाविद्यालयों की खास रुचि है जो निजी हैं।

पूर्व स्थापित तीनों विश्वविद्यालयों (जयपुर, जोधपुर व उदयपुर) के अशैक्षणिक कर्मचारियों ने भी राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय पुनर्गठन के लिए जारी अध्यादेशों का विरोध किया है। अध्यादेशों के मुताबिक अब किसी भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी किसी भी नवगठित विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। कर्मचारी चाहते हैं कि यह निर्णय उनकी इच्छा को वरीयता ते हुए पदोन्नति के साथ होना चाहिए।

विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन को लेकर केवल राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, उदयपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और जोधपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ खामोश हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने तो पिछले वर्ष चुनाव के दौरान स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय का आकार छोटा करने की बात कही थी। पर इसी संघ के पूर्व पदाधिकारी विश्वविद्यालय का आकार छोटा करने के विरोधी हैं। जयपुर के वरिष्ठ नागरिकों ने भी एक कमेटी बनाकर राजस्थान विश्वविद्यालय के नये स्वरूप का विरोध किया है। राज्य सरकार ने पुराने विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन और तीन नये विश्वविद्यालयों के सत्र इसी वर्ष प्रारम्भ करने की दृष्टि से जुलाई की बजाय अगस्त से शिक्षा सत्र शुरू कराने का फैसला किया था। पर सांकेतिक हड़तालों ने शिक्षा सत्र को ड़बड़ा दिया है।

दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि छात्र एवं वा नेता जहां विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन और व विश्वविद्यालयों की परिकल्पना से पूरी तरह वगत नहीं हैं, वहीं विश्वविद्यालय एवं महाद्यालय शिक्षक संघ के नेता निजी क्षेत्र के शिक्षकों और संचालकों को प्रतियोगिता से बचाने का न्दोलन रच रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय मानविकी पीठ के सभागृह में उपस्थित लगभग र छात्र एवं युवा नेता मुद्दे की गहराई से अनभिज्ञ था। बहरहाल 'माया' ने युवा जनता के प्रदेशाध्यक्ष जेन्द्र सिंह राठौड़ से नये विश्वविद्यालयों के ठन और पुरानों के पुनर्गठन के बारे में जानना हा तो उनका कहना था, "नये विश्वविद्यालय कुछ नहीं हैं, केवल राजस्थान विश्वविद्यालय को तोड़-मरोड़ कर अलग किये भाग हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमने संभागीय विश्वविद्यालयों की मांग की थी, जिसका मतलब हर्गिज यह नहीं था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय महाविद्यालयों को अजमेर विश्वविद्यालय में मिला दिया जाये और कोटा को पत्राचार संस्थान सौंप कर विश्वविद्यालय का नाम दे दिया जाये।" राठौड़ इस बात से सहमत नहीं हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के आवासीय बनने से उसका शैक्षिक स्तर सुधरेगा। उन्होंने 'माया' से कहा, "जोधपुर विश्वविद्यालय पहले से आवासीय है, उसका स्तर कितना सुधर गया?"

लेकिन विद्यार्थी परिषद के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य अरुण चतुर्वेदी ऐसे युवा नेता हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों का ज्ञान था। उनका कहना था, "कोठारी आयोग के अनुसार आदर्श विश्वविद्यालय वही होगा, जिसमें कम-से-कम ४० महाविद्यालय एवं तीस हजार छात्र सम्बद्ध हों, किन्तु राज्य सरकार ने प्रस्तावित प्रारूप से आदर्श विश्वविद्यालयों की परिकल्पना को ही नकार दिया है।" उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय को आवासीय बनाने के विरुद्ध वर्ष १९७१ के मोहन सिंह मेहता व १९७३ के श्रीमाली आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया।

स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया की प्रांतीय शाखा के महामंत्री फूलचंद ने कहा, "जो सरकार प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक नहीं पहुंचा सकी है, वह संभागीय विश्वविद्यालय खोलने का झांसा देकर छात्रों और शिक्षकों की एकजुटता को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है।" उनका मानना है कि शैक्षिक उत्कर्षता के नाम पर सरकार छात्रों को विभाजित करने का प्रयत्न कर रही है, जिसे हम पूरा नहीं होने देंगे।

आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की राजस्थान शाखा के महामंत्री रमेश शर्मा आंकड़ों से समझा रहे थे कि सरकार के वित्तीय साधन इतने नहीं हैं कि वह तीन और विश्वविद्यालयों का संचालन कर सके। ऐसे में संभागीय विश्वविद्यालयों के नाम पर राज्य सरकार ने साधनहीन विश्वविद्यालयों का गठन किया है, जिनसे निकला छात्र साधन-सम्पन्न विश्वविद्यालयों के छात्र के सामने कमजोर साबित होगा।

सत्तारूढ़ दल के छात्र एवं युवा संगठन मानविकी पीठ के सभागार से परे रहे। इन संगठनों के नेता सरकारी नीति के समर्थक हैं। इस सारे प्रकरण में तकलीफदेह स्थिति यह है कि राज्य

सेवा काल मे कम से कम दो पदोन्नति दी जाए
सभागीय आधार पर विश्वविद्यालयों का गठन किया जाए।
के निजी महा-
यों को राजस्थान
लय से सम्बद्ध
किया जाये।
जयपुर शहर

शिक्षा नीति का विरोध : शिक्षकों का प्रदर्शन

विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन को लेकर प्रदेश में खासा असंतोष है। इस असंतोष के लिए राज्य सरकार का प्रशासन जिम्मेदार है। गत २३ जून, १९८७ को राज्य सरकार ने चुने हुए शिक्षाविदों के समक्ष विश्वविद्यालयों का प्रस्तावित स्वरूप प्रस्तुत किया था। इस प्रस्तावित स्वरूप में राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर व जोधपुर विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र उनकी नगर परिषद की सीमाओं तक प्रस्तावित था। शिक्षाविदों के बहुमत ने इस स्वरूप के खिलाफ अपनी राय जाहिर की।

सरकार अथवा किसी कुलपति ने विश्वविद्यालयों की परिकल्पना पर प्रकाश नहीं डाला है। माया ने इस सन्दर्भ में राज्य सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री दामोदर आचार्य से साक्षात्कार चाहा, पर वह दौरों अथवा बैठकों में ही इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस 'अमहत्वपूर्ण' मसले पर बातचीत करने का समय निकालना उचित नहीं समझा। शिक्षा से संबंधित प्रशासक साक्षात्कार देने से कतराते रहे।

दरअसल, विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन को लेकर प्रदेश में खासा असन्तोष है। इस असन्तोष के लिए राज्य सरकार का प्रशासन जिम्मेवार है। गत २३ जून, १९८७ को राज्य सरकार ने चुने हुए शिक्षाविदों के समक्ष विश्वविद्यालयों का प्रस्तावित स्वरूप प्रस्तुत किया था। इस प्रस्तावित स्वरूप में राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर व जोधपुर विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र उनकी नगर परिषद की सीमाओं तक प्रस्तावित था। शिक्षाविदों के बहुमत ने इस स्वरूप के खिलाफ अपनी राय जाहिर की।

प्रस्तावित स्वरूप : राज्य सरकार ने आठ अप्रैल, १९८७ को सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के नियम एवं प्रारूप बनाने के लिए महाविद्यालय के पूर्व निदेशक एन०एम० कोठारी की अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने जून में अपना प्रारूप पेश किया, जिसे शिक्षाविदों ने नकार दिया।

कोठारी कमेटी ने अपनी प्रायोजना में राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर पूर्व में हुए अध्ययनों को आधार बनाया। इस सन्दर्भ में कमेटी ने वर्ष १९७१ की मेहता कमेटी की रिपोर्ट, वर्ष १९७४ की श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट और वर्ष १९८० की माथुर कमेटी की रिपोर्ट का उपयोग किया।

वैसे राजस्थान में उच्च शिक्षा का इतिहास यह है कि १९४१ तक कुल जनसंख्या का ५.५१ प्रतिशत शिक्षित था। आजादी के बाद आठ जनवरी, १९४७ में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके अधिकार क्षेत्र से अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र के महाविद्यालय मुक्त थे। राजपूताना विश्वविद्यालय परिसरविहीन सम्बद्ध विश्वविद्यालय था, जिसके अन्तर्गत दस स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय आते थे और कुल छात्रों की संख्या मात्र ३ हजार ११८ थी। १९५६ में जब अजमेर और मेवाड़ का विलय राजस्थान में हुआ, तो राजपूताना विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। स्व० डा० मोहनसिंह मेहता के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग हर विषय का अध्ययन होने लगा था। उच्च शिक्षा के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप १९६२-६३ में जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जोधपुर विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र जोधपुर शहर तक सीमित रहा। वर्ष १९६४ में उदयपुर विश्वविद्यालय को भी कृषि-विश्वविद्यालय से बदल कर सामान्य विश्वविद्यालय बना दिया। उस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय में २५,३६० छात्र, जोधपुर विश्वविद्यालय में ४,३४९ छात्र और उदयपुर विश्वविद्यालय में ३,९५२ छात्र थे। पर यही संख्या वर्ष १९७०-७१ में तीनों विश्वविद्यालयों में दुगनी से अधिक हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप नये विश्वविद्यालय खोलने की मांग उठी। तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मांग के औचित्य को समझते हुए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डा० के०एल० श्रीमाली की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी को प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए, अगले दस वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संभावित जरूरतों को दृष्टि में रख कर अध्ययन केन्द्रों के स्वरूप में परिवर्तन और नये विश्वविद्यालयों के गठन के सम्बन्ध में सुझाव देने थे।

श्रीमाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया था कि अगर किसी विश्वविद्यालय को विद्वज्जनों के समूह के रूप में विकसित कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से सम्पन्न करना हो, तो उसका आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर कमेटी की सिफारिश थी कि आदर्श विश्वविद्यालय के लिए छात्रों की संख्या दस और पन्द्रह हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में तीस हजार से अधिक न हो। कमेटी ने राजस्थान विश्वविद्यालय पर बढ़ते हुए भार को देखते हुए सिफारिश की थी कि राज्य में अजमेर, बीकानेर और कोटा में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। कमेटी ने स्पष्ट किया था कि इन्हें प्रारम्भ में छोटे स्तर पर तथा बाद में संबद्ध कालेजों को देखते हुए सभी विषयों में शोध के लिए तैयार किया जा सकता है।

महाविद्यालय खोलने का सिलसिला : राज्य सरकार ने इन सिफारिशों पर अमल करने के बजाय उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए सम्बद्ध महाविद्यालय खोलने का सिलसिला जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि वर्ष १९७९-८० में राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों की संख्या १७० हो गयी और छात्र १९७३ की सत्तर हजार की संख्या के मुकाबले एक लाख अठारह हजार हो गये। इसके साथ ही सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय संकाय के प्राध्यापकों के बीच विभिन्न मसलों पर विरोध बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने एक बार फिर १९७९ में राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर एम०वी० माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी को नियुक्त किया। इस कमेटी को उदयपुर विश्वविद्यालय के पुनर्गठन तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों को तीन क्षेत्रों में विभाजित करते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध तक सीमित करने व किसी एक विश्वविद्यालय को सम्बद्धता और परीक्षा लेने की जिम्मेदारी सौंपने पर राय देना था।

जनता सरकार द्वारा नियुक्त की गयी माथुर कमेटी ने जोधपुर विश्वविद्यालय में यथास्थिति बनाये रखने की सलाह दी, जबकि उदयपुर विश्वविद्यालय से कृषि संकाय को अलग कर प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने वाले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का परामर्श दिया। साथ ही तीनों विश्वविद्यालयों को भौगोलिकता के आधार पर सम्बद्धता का अधिकार देने का माथुर कमेटी ने विरोध किया। कमेटी का मानना था कि ऐसा करने पर उदयपुर व जोधपुर विश्वविद्यालयों का एकात्मक स्वरूप भी समाप्त हो जायेगा और राजस्थान विश्वविद्यालय पर बढ़े सम्बद्ध महाविद्यालयों के भार में कोई कमी नहीं होगी। आज भी भौगोलिक आधार पर अगर राजस्थान के महाविद्यालयों को बांटा जाये, तो जोधपुर क्षेत्र में तेरह, उदयपुर में २१, अजमेर में ३१, कोटा में २२, बीकानेर में ३७ और जयपुर क्षेत्र में ८२ कालेज आते हैं।

माथुर कमेटी ने स्थापित तीनों विश्वविद्यालयों में से किसी एक विश्वविद्यालय को सम्बद्ध कालेजों

साक्षात्कार/प्रो० रत्नप्रकाश कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय पर से प्रेशर कम किया जाये

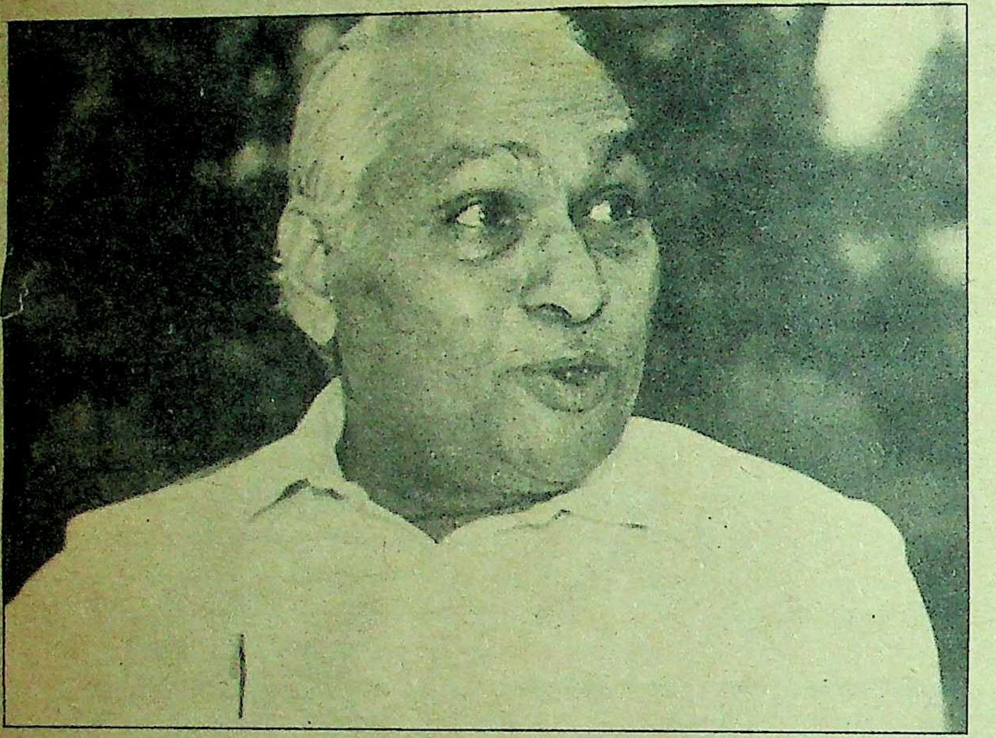

लखनऊ विश्वविद्यालय से आये प्रोफेसर रत्नप्रकाश अग्रवाल राजस्थान विश्वविद्यालय के ऐसे कुलपति हैं, जो प्रारंभ से ही विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट बनाने के लिए आतुर हैं। उनके आलोचक मानते हैं कि विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन और विशेष रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय को आवासीय बनाने में प्रो० अग्रवाल की विशेष भूमिका रही है। 'माया' ने इस सन्दर्भ में प्रोफेसर अग्रवाल से लंबी बातचीत की है। प्रस्तुत हैं,बातचीत के अंश :

माया : राजस्थान विश्वविद्यालय को आवासीय स्वरूप देने और इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अजमेर विश्वविद्यालय से जोड़ने पर जो विवाद उठा है, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है ?

अग्रवाल : यह कहानी शुरू होती है २० जनवरी, सन् १९७९ से, जबकि उस वक्त के शासन ने एम०वी० माथुर कमेटी का गठन किया। इसमें और भी शिक्षाविद् थे, जिन्हें राजस्थान में हायर एजूकेशन के संबंध में अध्ययन करके सुझाव देने थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब इसमें काफी कालेज हो गये हैं, भार काफी बढ़ गया है। हम लोग शैक्षिक स्तर उतना नहीं रख पा रहे हैं, जितना पहले था। इस सन्दर्भ में कुछ सुझाव दिये, जिनमें पहला सुझाव था कि जोधपुर युनिवर्सिटी आवासीय है, उसे बना रहने दिया जाये और राजस्थान विश्वविद्यालय को भी आवासीय बना दिया जाये। इसकी जगह ऐसी एफिलिएटिंग (सम्बद्ध) युनिवर्सिटीज बनायी जायें, जो शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास की आधुनिक पद्धति के लिए आदर्श बन सकें। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी एक बनायी जाये और उदयपुर युनिवर्सिटी अलग की जाये। यह १९८० की सिफारिश है। इसके बाद कालेजों की संख्या बढ़ी और वे सब राजस्थान युनिवर्सिटी से सम्बद्ध हुए। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों पहले तक लगभग २२५ कालेज राजस्थान युनिवर्सिटी के पास थे। जो नहीं बढ़ रहा था, उसके लिए किसी भी कुलपति के पास इतना समय नहीं होता था कि वह ध्यान दे।

इस वर्ष जनवरी में राज्य सरकार ने एक पत्र इस सन्दर्भ में यू०जी०सी० (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) को लिखा। यू०जी०सी० ने इसका अध्ययन कर एक कमेटी का गठन किया, जिसका सदस्य मैं भी था। यू०जी०सी० ने यह कमेटी केवल राजस्थान को निगाह में रखकर गठित नहीं की थी, बल्कि इस रूप में की थी जिससे एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी (सम्बद्ध विश्वविद्यालय) का एक नया माडल तैयार हो सके, विशेषकर राजस्थान युनिवर्सिटी के प्रकरण में। १७ जून को इस कमेटी की बैठक हुई, पर इसका संबंध राजस्थान में नवगठित विश्वविद्यालयों से नहीं था। शासन ने यहां तो मार्च में ही तीन विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया था। कोटा युनिवर्सिटी के लिए तय था कि वहां पर ओपन युनिवर्सिटी चलेगी और मेरी मान्यता है कि जब तक हम नान फारमल एजूकेशन (अनौपचारिक शिक्षा) को नहीं बढ़ायेंगे, तब तक विश्वविद्यालयों पर से भार कम नहीं होगा। और आज यह नितांत आवश्यक हो गया है कि विश्वविद्यालयों पर से प्रेशर कम किया जाये। इस आशय से कोटा युनिवर्सिटी बनी, अजमेर को एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी (सम्बद्ध विश्वविद्यालय) बनाया गया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, यह शासन का निर्णय है। हां, यू०जी०सी० की कमेटी बैठक में हमने इसके प्रारूप को जरूर मान्यता दी है।

माया : राजस्थान विश्वविद्यालय को आवासीय बनाने और सम्बद्ध महाविद्यालयों को अजमेर विश्वविद्यालय से जोड़ने को लेकर शिक्षक बहुत नाराज हैं ?

अग्रवाल : मैं क्यों कहूं कि उनका सोचना गलत है। वैसे, ऐसा तो पहले भी था। उदयपुर विश्वविद्यालय होने के बावजूद उदयपुर के कालेज राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। जो सोचते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना सारा भार अजमेर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया, वह गलत सोचते हैं। आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय को उतनी ही परीक्षाएं लेनी पड़ेंगी, जितनी अजमेर अथवा कोटा विश्वविद्यालय को।

माया : राजस्थान विश्वविद्यालय का आकार छोटा होने से क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय लाभों में कमी नहीं आयेगी ?

अग्रवाल : यह नितांत भ्रम है। हम लोगों को यू०जी०सी० कोई भी ग्रांट कालेजेज (महाविद्यालयों) के लिए नहीं देती थी। कालेज डेवलपमेंट के लिए जो पैसा यू०जी०सी० देती थी प्लान पीरियड में, वह कालेजों को दिया जाता था। बल्कि अब तो नयी युनिवर्सिटीज को भी प्लान पीरियड में उनके डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग पैसा मिलेगा। ऐसे में यह कहना कि हमारी ग्रान्ट्स कम हो जायेगी, यह गलत-

फहमी है। मुझे आशा है, राजस्थान शासन ने जो बड़ा कदम (विश्वविद्यालय पुनर्गठन का) उठाया है, उसके लायक हम होंगे।

माया : आप नहीं मानते कि नये विश्वविद्यालयों के निर्माण के साथ शासन का सीधा हस्तक्षेप विश्वविद्यालय में होने लगा है ?

अग्रवाल : मैं समझता हूं कि नये विश्वविद्यालयों के लिए जो आई०ए०एस० कुलपति बनाये गये हैं, उनकी स्थिति एक कार्यवाहक कुलपति जैसी है। मेरी ऐसी धारणा है, राज्य सरकार निश्चित रूप से शिक्षाविदों को ही यह काम सौंपेगी। वैसे इनके बनाने से फिलवक्त लाभ यह है कि यह संभागीय आयुक्त हैं जो अपने क्षेत्र से वाकिफ हैं। इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों का इन्फ्रा स्ट्रक्चर बिल्ड करने में सहूलियत होगी। जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने शिक्षा के मामलों में कभी शासन का हस्तक्षेप महसूस नहीं किया। मुझे इस बात का गर्व है और मैं शासन को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि मुझे एडमीशन तक के लिए कभी बाध्य नहीं किया।

माया : नये अध्यादेशों के मुताबिक विश्वविद्यालय कर्मचारियों के स्थानांतरण के जो अधिकार शासन ने हासिल किये हैं, उनके संबंध में आप क्या कहेंगे ?

अग्रवाल : अगर, आप अध्यादेश पढ़ें तो उनमें केवल यह लिखा है कि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए...ट्रांजिट्री पीरियड के लिए सरकार ने यह अधिकार ले लिया है। विश्वविद्यालय की संपत्ति इधर-से-उधर जायेगी, अगर उसे देखनेवाले लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए केवल यह ट्रांजिट्री फेज है। इसके विषय में काफी भ्रम शिक्षकों और हमारे कर्मचारियों में हैं, पर मैंने शिक्षा सचिव से बात कर सारी स्थिति स्पष्ट कर ली है। हमारे कर्मचारी जैसे आदेश चाहते थे, वैसे मैंने आदेश भी किये हैं।

माया : कहा जा रहा है कि आवासीय विश्वविद्यालय के छात्र और दूसरे छात्र की हैसियत में भारी अंतर हो जायेगा। छात्र नेता इस मुद्दे पर विशेष रूप से नाराज हैं।

अग्रवाल : और कल तक महाविद्यालयों के साथ हमारा नाम ही तो जुड़ा था, स्तर सुधारने का काम तो उन्हें खुद ही करना होता था और करना चाहिए। केवल हमारा पाठ्यक्रम ही पढ़ाते थे। यह भी एक चुनौती है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना पाठ्यक्रम बनाकर पढ़ायें और राजस्थान विश्वविद्यालय को भी इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपने छात्रों को विश्वस्तरीय शैक्षिक स्तर पर लाये। ■

का विश्वविद्यालय बनाने के बजाय नया सम्बद्धता वाला विश्वविद्यालय खोलने का परामर्श दिया। इस विश्वविद्यालय का शैक्षिक स्तर स्थापित विश्वविद्यालयों जैसा रहे, इसके लिए विभिन्न विषयों के पारंगत आचार्यों को इसके अध्ययन मण्डल में मनोनीत करने का परामर्श दिया। साथ ही विस्तार के साथ बताया कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय को किस तरह शैक्षिक दृष्टि से स्थापित विश्वविद्यालयों की तरह से सम्पन्न बनाया जा सकता है।

तत्कालीन राज्य सरकार इन परामर्शों पर विचार करती, उससे पहले ही शासन बदल गया। नतीजा यह हुआ कि विश्वविद्यालयों के वर्तमान पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालेजों की संख्या एक सौ सत्तर से बढ़ कर दो सौ सोलह हो गयी। सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों सहित राजस्थान विश्वविद्यालय को तीन लाख छात्रों की परीक्षा लेने का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी निभानी होती थी। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल उपस्थित हो गया था। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोठारी कमेटी ने उक्त अध्ययनों को आधार बनाते हुए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर को उत्कृष्ट बनाने की पूरी योजना प्रस्तुत की है।

इस योजना के तहत ऐसी स्वायत्त क्षेत्रीय कौंसिलों का गठन किया जायेगा जो अजमेर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों को नियंत्रित करेगी। इसी तरह माथुर कमेटी की सिफारिश को मानते हुए राज्य सरकार ने बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया है, तो कोटा में स्थापित विश्वविद्यालय को खुले विश्वविद्यालय का नाम दिया है।

घालमेल : बहरहाल प्रदेश के विभिन्न छात्र एवं युवा संगठनों व महाविद्यालय शिक्षक संगठनों की नाराजगी की वजह विश्वविद्यालयों के साथ संभागीय कालेजों का बंटवारा भौगोलिक आधार पर न करना रहा है। भौगोलिक आधार पर संभागीय कालेजों का बंटवारा न होने की वजह से अब हर शहर में कई विश्वविद्यालयों का हस्तक्षेप रहेगा। मसलन जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ-साथ अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज चलेंगे। ठीक इसी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय का पत्राचार संस्थान अब कोटा विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में नजर आयेगा। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अलावा, वहां का कृषि महाविद्यालय बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा बनेगा। अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अलावा इंजीनियरिंग व मेडिकल कालेज, राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे। इसी तरह जोधपुर में जोधपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोटा औ अजमेर विश्वविद्यालय से जुड़े कालेज होंगे

इन संगठनों ने नये विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर जारी किये गये अध्यादेशों से उत्प स्थिति पर भी एतराज किया है। जारी अध्यादेश से राज्य सरकार को विभिन्न विश्वविद्यालयों कर्मचारियों के स्थानान्तरण का ऐसा हथिया प्राप्त है, जिसके नाजायज इस्तेमाल न होने कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकार ने तीनों न विश्वविद्यालयों के कुलपति संभागीय आयुक्त यान आई०ए०एस० अधिकारी नियुक्त किये हैं। इ नियुक्तियों को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता लिए खतरा मानते हुए शैक्षिक माहौल में नौकरशाही की दखलंदाजी करार दिया जा रहा है इन स्थितियों में छात्र व युवा संगठनों द्वारा तैया किया गया मांग-पत्र काफी विस्फोटक हो सकत है, जिसमें छात्र संघों के चुनावों की मांग के अतिरि सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश जैस रोचक मांग शामिल है।

> **— जारी अध्यादेशों से राज्य सरकार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण का ऐसा हथियार प्राप्त है, जिसके नाजायज इस्तेमाल न होने की कोई गारंटी नहीं है**

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोटा के खु विश्वविद्यालय तथा बीकानेर के राजस्थान कृ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जारी अध्यादे गजट में प्रकाशित हुए हैं। इनका अध्ययन करने बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडीकेड शिक्षकों के प्रतिनिधि डा० एस०डी० मिश्र, सीने में शिक्षकों के प्रतिनिधि डा० मधुकर श्याम चतुर्वेदी तथा राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक सं के पूर्व अध्यक्ष डा० आर०बी० सिंह ने एक संयु बयान में सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों का तेज से सरकारीकरण का आरोप लगाया है।

अध्यादेशों में उक्त विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डल के संगठन को अधिनियम परिभाषित कर के बजाय साधारण परिनियमों का अंग बना दिय गया है, जिन्हें सरकारी संकेत पर कभी भी बदल जा सकता है। अधिनियम के साथ जोड़े गये परिनियमों के अनुसार प्रबन्ध मण्डल में शिक्ष व छात्रों के प्रतिनिधियों का कोई प्रावधान न है जबकि राज्य सरकार के शिक्षा, वित्त व आयोजना विभाग के सचिवों को प्रबन्ध मंडल क स्थायी सदस्य बनाया गया है। ■

विकास कलकत्ता का या कालेधन का ?

कलकत्ता शहर के विकास के सिलसिले में १९ नंबर, सरोजनी नायडू सरणी अर्थात् 'रडन स्क्वैयर' में कार्मशियल कांप्लेक्स और आडीटोरियम के निर्माण का ठेका कलकत्ता नगर निगम के कम्युनिस्ट मेयर ने अन्य टेंडरों की उपेक्षा करके एक मामूली कंपनी की ओट में उस उद्योगपति अरुण बाजोरिया को दे दिया, जिसके मकान से आयकर विभाग ने ५ करोड़ रुपए का कालाधन पकड़ा था। कलकत्ता के मेयर इस सबके पीछे मुख्यमंत्री ज्योति बसु के भांजे सांसद अमल दत्त की भूमिका बताते हैं और अमल दत्त इससे इनकार करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में चर्चा है कि इन ठेकों के एवज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कोष के लिए करोड़ों रुपए वसूले गये हैं। ज्योति बसु सरकार के सामने आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि वह कलकत्ता शहर के विकास के लिए आर्थिक अपराधियों के सामने हाथ पसारने को मजबूर हो गयी है ? क्या पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी भी कालेधन से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है ?

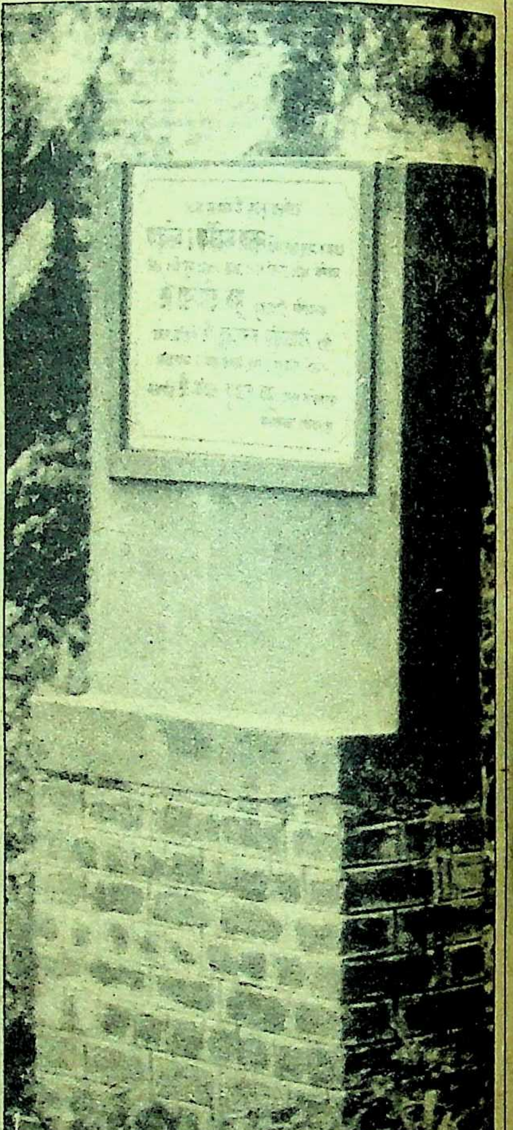

सिद्धांतों की कब्र : मुख्यमंत्री ज्योति बसु (ऊपर बायें) द्वारा 'रडन स्क्वैयर' पर कामर्शियल कांप्लेक्स का शिलान्यास

१४ जून, १९८७ को कलकत्ता नगर निगम ने विज्ञप्ति जारी की कि १९ नंबर, सरोजिनी नायडू सरणी में कार्मशियल कांप्लेक्स और चार आडीटोरियम निर्मित कराये जायेंगे। १४ जून को मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उसका शिलान्यास किया। उस समय कोई नहीं समझ सका कि १९ नंबर, सरोजिनी नायडू सरणी ही 'रडन स्क्वैयर' है। लेकिन जब यह लोगों को पता चला तब हो-हल्ला होने लगा। रहस्यमय टेंडर के जरिये दो हजार रुपए की पूंजीवाले एच०के० सेन टर्नकी एसोसियेट्स कंपनी को आर्डर मिल गया। बाद में पता चला कि यह तो नाम के वास्ते हैं। इस पूरे प्रकरण के पीछे आर्थिक अपराधी अरुण बाजोरिया हैं। इसी के बाद रडन स्क्वैयर को लेकर लेन-देन का मामला उछलने लगा, लेकिन सरकार एच०के० सेन टर्नकी एसोसियेट्स की महिमा का प्रचार करने में लगी रही।

सिर्फ रडन स्क्वैयर ही नहीं, कलकत्ते की और एक खुली सरकारी जमीन का बिना प्रीमियम लिये कलकत्ता नगर निगम ने एच०के० सेन टर्नकी को प्रोजेक्ट सौंप दिया है। यह जमीन रडन स्क्वैयर से सौ गज दूर है। इसका पता है—१८५/१, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड। इस तीस कट्ठा जमीन पर कार्मशियल कांप्लेक्स बनेगा। भाजपा कौंसिलर श्यामसुंदर गोयनका का आरोप है कि एच०के० सेन मेयर के अमरीका-प्रवासी बेटे का जिगरी दोस्त है और इसीलिए मेयर एच०के० सेन के प्रति इतनी उदारता दिखा रहे हैं।

पृष्ठभूमि : रडन स्क्वैयर और वह जमीन एच०के० सेन को देने के पीछे छोटा-सा इतिहास है। कानूनन भारत की कोई भी सरकारी जमीन, मकान या पार्क लीज पर देने या दूसरे को सौंपने के लिए टेंडर आमंत्रित

करना पड़ता है। रडन स्क्वैयर और १८५/१, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड की जमीन को 'विकसित' करने के लिए सीधे टेंडर नहीं मांगा गया। नगर निगम ने एक विज्ञप्ति जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया कि १९ नंबर, सरोजिनी नायडू सरणी स्थित स्क्वैयर को विकसित करने के लिए आइडिया चाहिएं। जो इस काम को करना चाहते हैं, वे अपनी आर्थिक स्थिति और अनुभव का विवरण दें। कुल २८ पार्टियों ने इस विज्ञप्ति का उत्तर दिया। उसके बाद संबंधित अधिकारियो ने उनको बताया कि आप लोग मार्केट और पार्क डिवीजन के श्री जाना से बात कीजिए। श्री जाना ने उन लोगों को बताया, आप लोगों का आइडिया नगर निगम को पसंद नहीं है। बाद में सबको पता चला कि नगर निगम ने वह काम एच०के० सेन टर्नकी एसोसिएट्स कंपनी को दे दिया है।

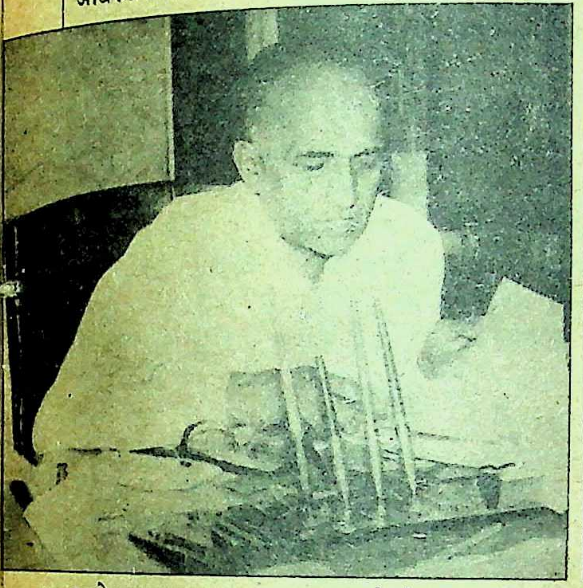

कालेधन का स्वागत : कलकत्ता के मेयर कमल बसु

करोड़ों के लेन-देन का आरोप : मुख्यमंत्री ज्योति बसु के भांजे सांसद अमल दत्ता

मजे की बात है कि 'हित मंगल एसोसियेट्स' ने अपने टेंडर में बताया था कि हमारी तरफ से छह सौ रुपए प्रति वर्ग फुट प्रीमियम दिया जायेगा और हम ही पूरा कांप्लेक्स और आडीटोरियम बना देंगे। इस टेंडर के मुताबिक काम होने पर नगर निगम को नौ करोड़, साठ लाख रुपए का प्रीमियम मिलता। 'पाम प्रापर्टीज' नाम की दूसरी पार्टी ने बताया था कि हम अपने खर्चे से दिल्ली की तरह 'अप्पूघर' और स्वीमिंग पूल के साथ कांप्लेक्स बना देंगे। जापान से आयातित 'अप्पूघर' का नाम सभी जानते हैं। लेकिन एक करोड़ रुपए के फाइनेंसियल स्टेटस वाले 'पाम प्रापर्टीज' का टेंडर न जाने किस कारण से रद्द हो गया। इन सबको पीछे छोड़कर दो हजार रुपए की पूंजी के मालिक एच०के० सेन काम पा गये, जिनके पीछे आर्थिक अपराधी अरुण बाजोरिया हैं।

१९९० तक कलकत्ते का संपूर्ण विनाश : कांग्रेस कौंसिलर शिव कुमार खन्ना

एच०के० सेन टर्नकी ग्रुप को कलकत्ते के विकास का यह उत्तरदायित्व सौंपने के बाद ही गुल खिलने लगा। एच०के० सेन ग्रुप की तरफ से बताया गया कि उसकी मदद के लिए बाजोरिया ग्रुप २० करोड़ रुपए देगा। बाजोरिया ग्रुप की सहायता से वह रडन स्क्वैयर से नगर विकास का कार्य शुरू करेगा। यह वही अरुण बाजोरिया है, जिसके कार्यालय पर १६ जुलाई, १९८७ को आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा था। इस आकस्मिक छापे में आयकर विभाग के लोगों के हाथ ५ करोड़ रुपए लगे। यह धन पूरा-का-पूरा काला था। कार्यालय के अलावा बाजोरिया साहब के घर और जूट मिल पर भी कई बार छापा पड़ा। इसी बीच आयकर विभाग पर दबाव पड़ने लगा, लेकिन आयकर वालों ने चंदननगर की उनकी ७५० बीघा जमीन का भी पता लगा लिया। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के शेयर भी दूसरे के नामों से बाजोरिया साहब के पास होने की खबर विभाग को है। उनकी जूट मिल के हिसाब-किताब में भी गड़बड़ी पायी गयी थी।

कानून किसने तोड़ा : लेकिन रडन स्क्वैयर के मामले में अचानक कलकत्ता नगर निगम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? कलकत्ते में जहां हरियाली का नाम मिटता जा रहा है, वहां इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया? फिर मजे की बात यह है कि नगर निगम कानून का नाम लेकर ला मार्टीनियर स्कूल को क्यों रडन स्क्वैयर के पास किसी तरह का निर्माण करने नहीं दिया गया? इस तरह रडन स्क्वैयर को लेकर एक व्यवसायी और राजनीतिक नेताओं के बीच जो गठबंधन हुआ, वह अनेक सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठा कि १९ नंबर, सरोजिनी नायडू सरणी खुली जमीन है या पब्लिक पार्क? नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार वह जगह ६३ नंबर वार्ड में है। यदि वह भूखंड पब्लिक पार्क है, तो कलकत्ता म्युनिसिपल नगर निगम ऐक्ट १९८० के अंतर्गत क्या उसे किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जा सकता है? यदि पार्क को लीज पर दिया जाये, तो उसके लिए कितना दाम मिलना चाहिए? इस तरह के कानूनी सवालों के साथ अन्य कई समस्याएं सामने आयीं, क्योंकि १९८० के कानून के मुताबिक धारा ५४१ और ५४२ के अंतर्गत किसी पार्क, स्क्वैयर या गार्डन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कलकत्ता नगर निगम ने स्वयं अपना बनाया कानून तोड़ा।

गत १० जुलाई को विपक्षी नेता कांग्रेस कौंसिलर शिवकुमार खन्ना ने मेयर कमल बसु को एक पत्र लिखा। पत्र का आशय यह था कि किन शर्तों के आधार पर रडन स्क्वैयर के बारे में ऐसा निर्णय लिया गया, यह बताया जाये। खन्ना के पत्र के उत्तर में मेयर ने केवल इतना ही सूचित किया कि अनिवार्य कारण से मैं उन शर्तों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मेयर के इस उत्तर ने स्वाभाविक रूप से कांग्रेस खेमे को आंदोलित कर दिया। शिवकुमार खन्ना ने इस प्रतिवेदक को बताया कि मेयर 'राजनीतिक' कारण से ही इस तथ्य को छिपा रहे हैं। उनकी यह चुप्पी 'रहस्यमय' है। शिवकुमार खन्ना के वक्तव्य के अनुसार इस घटना के पीछे करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है।

प्रमुख भूमिका : कलकत्ता नगर निगम ने रडन स्क्वैयर के मामले में व्यवसायियों के प्रति जो उदारता दिखायी, उससे अनेक प्रकार के संदेह पैदा होने लगे। विधायक सुलतान अहमद ने बताया, "कलकत्ता नगर निगम इस समय सब कुछ तबाह करने पर उतारू है। वह काले धन के मालिक कुछ व्यवसायियों के हाथों में कलकत्ते का भविष्य सौंप देना चाहता है। फिर तो ऐसा भी समय आयेगा कि कलकत्ता शहर के सामान्य लोग कैनिंग या लक्ष्मीकांतपुर जाकर रहेंगे। गैरबंगाली व्यवसायी कलकत्ते के मालिक बन जायेंगे।" अहमद साहब के अनुसार रडन स्क्वैयर और अन्य बाजारों के लेन-देन से करोड़ों रुपए पार्टी फंड में आ रहे हैं। अरुण बाजोरिया के प्रति वाम मोर्चे का विशेष लगाव है। वक्त-जरूरत पर व्यवसायी बाजोरिया का सौजन्य भी वाम-मोर्चे के लोगों को मिलता रहता है।

एक तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का व्यवसायियों के प्रति आक्रोश मुखर है, तो दूसरी तरफ इस लेन-देन के पीछे राजनीति और रुपए की प्रमुख भूमिका होने के कारण जनमानस में असंतोष है। भाजपा कौंसिलर शांतिलाल जैन ने भी बताया कि रडन स्क्वैयर की बदौलत नगर निगम अपने लोगों का भविष्य सुखद बनाने में लगा हुआ है। यह एक प्रकार का निर्लज्ज भ्रष्टाचार है।

कांग्रेस विधायक-कौंसिलर सुलतान अहमद ने बताया कि मोर्चा सरकार नगर निगम के माध्यम से इस शहर का स्वामित्व व्यवसायियों को सौंप देना चाहती है। हमारे पास खबर है कि कुछ दिनों में [illegible] की कई सरकारी जमीनें उनको दे दी जायेंगी। उन [illegible]

मार्केटों में आठ-आठ मंजिली बिल्डिंगें बन रही हैं। उन बिल्डिंगों के एक-एक कमरे की कीमत पचास हजार रुपए ठहरती है। यह सब तो सफेद धन में है। फिर लाखों रुपए किन लोगों की जेब में जा रहे हैं? अहमद साहब की यह भी शिकायत है कि नगर निगम के लोगों ने आपस में यह तय किया है कि इस शहर के सभी सरकारी आवास व्यवसायियों को दे दिये जायेंगे। इसका कारण यह है कि विकास कार्य के लिए नगर-निगम के पास धन नहीं है।

असली इरादे : कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि एच०के० सेन को सामने रखकर बाजोरिया को ही वह कार्मशियल कांप्लेक्स देना कार्पोरेशन का असली इरादा है। फिर सामान्य लोगों को वंचित कर उस कांप्लेक्स के कमरे विभिन्न गैर-बंगाली व्यवसायियों को दिये जायेंगे। सुलतान अहमद के वक्तव्य के अनुसार उस एक-एक कमरे से लाखों रुपए का गैर-कानूनी कालाधन वसूला जायेगा। यह रकम पार्टी-फंड में जायेगी। इसी बीच चार मार्केटों से दस लाख रुपए से अधिक काला धन वसूला गया है। इस कांप्लेक्स में कम-से-कम साठ कमरे बनाये जा रहे हैं। अहमद साहब का ख्याल है कि इन कमरों से कई करोड़ रुपये मिल जायेंगे। उनके अनुसार इस लेन-देन में कई वामपंथी नेता शामिल हो सकते हैं।

बताया जाता है कि इस काम में नगर निगम में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा बहुत आगे है। पिछले विधान सभा चुनाव के समय ही व्यवसायी अरुण बाजोरिया के साथ मेयर और कई अन्य बड़े नेताओं की गुप्त बैठक हुई थी। उसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि रडन स्क्वैयर के विकास कार्य में बागडोर बाजोरिया के हाथ में रहेगी। लेकिन शर्त यह रही कि बाजोरिया अपने मुनाफे से अच्छी-खासी रकम फ्रंट को देंगे। इसके अलावा और जो चार मार्केट हैं, उसमें भी नगर निगम हर मार्केट के पीछे दो लाख रुपए पार्टी फंड में चाहता था। यह रकम न दे पाने के कारण न्यू अलीपुर मार्केट का स्वामित्व बाजोरिया ग्रुप से छीन लिया गया। न्यू मार्केट में तो पचास हजार का कमरा तीन-चार लाख रुपए में बिका। ऐसे जो रकम आयी उसका सत्तर प्रतिशत काला धन है और उसका एक हिस्सा अलीमुद्दीन स्ट्रीट (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय) के फंड में गया।

नगर निगम के मेयर कमल बसु के अनुसार नगर का विकास कार्य व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं को देने पर पार्कों और स्क्वैयरों का भविष्य उज्ज्वल होगा। लाखों रुपए हवा में उड़ने लगेंगे। लेकिन उस कार्मशियल कांप्लेक्स की दुकानें किनको मिलेंगी, मध्यमवर्गीय लोगों को या बाजोरिया जैसे पूंजीपतियों को? शिवकुमार खन्ना ने बताया, "सत्यनारायण पार्क में भूगर्भ बाजार बनवाकर वे लोग जो फायदा नहीं कमा सके, उसी को 'रडन स्क्वैयर' में पूरा कर लेंगे। देखना है, आगे क्या होता है? लाखों रुपए का खेल शुरू हो गया है। हो सकता है: कभी पश्चिम बंगालवासियों को अपना प्यारा कलकत्ता छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाये।

गैरबंगाली कलकत्ता के मालिक बन जायेंगे : विधायक सुलतान अहमद

विकास के लिए कालाधन : कलकत्ते के विकास के लिए कलकत्ते के मेयर कमल बसु ने 'काले धन' का स्वागत किया है। व्यवसायी यदि शहर का विकास कर सकते हैं तो बुरा क्या? आर्थिक अपराधी अरुण बाजोरिया के २० करोड़ रुपए से रडन स्क्वैयर को नया जीवन मिलने जा रहा है। कलकत्ते के विभिन्न पार्कों और बाजारों को व्यवसायियों के हवाले कर देने का काम इस बीच पक्का हो चुका है। बताया जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ही अरुण बाजोरिया ने कई वामपंथी नेताओं को दावत देकर संतुष्ट कर लिया था।

बताया जाता है कि नगर निगम के वामपंथी ब्लू प्रिंट के अनुसार कलकत्ते का ७५ प्रतिशत स्वामित्व गैर-बंगाली व्यवसायियों को सौंप दिया जायेगा। गिरीश पार्क और भवानीपुर का गांजा पार्क उनको सौंपने का प्रयास पालिका मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तत्परता से विफल हुआ। ट्रैंगूलर पार्क, लियोनार्ड पार्क और रवींद्र सरोवर का दायित्व भी उन्हीं को सौपा जा रहा है। विपक्षी नेता शिवकुमार खन्ना का आरोप है कि १९९० तक इसी तरह कलकत्ता विनाश-यज्ञ का काम पूरा हो जायेगा। अलीपुर से कैमक स्ट्रीट तक ९० प्रतिशत जमीन गैर-बंगालियों के कब्जे में जा चुकी है। दक्षिण कलकत्ते के चिल्ड्रेंस पार्क को इस बीच दो भागों में बांटा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और सरकार की उदारता के कारण नगर निगम के कानून का उल्लंघन कर कुछ सिंधियों और मारवाड़ियों के प्रयास से बहुमंजिली इमारतें बनायी जा रही हैं। कलकत्ते भर में नगर निगम की जमीन पर अनेक तालाब पाटने का काम चालू है। उन स्थानों पर भी बहुमंजिली इमारतें बनने लगी हैं। रडन स्क्वैयर, पार्क, तालाब और सरकारी जमीन काले धन के मालिकों को सौंप देने में कलकत्ते के मेयर कमल बसु पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम किया है।

२९ जून, १९८७ को मेयर कमल बसु घोषणा कर चुके थे, "रडन स्क्वैयर का डेवलपमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने एक संस्था के नाम की सिफारिश की थी। लेकिन उस संस्था के पास योग्यता और अनुभव की कमी थी। इसलिए उसे काम नहीं दिया गया, लेकिन एच०के० सेन टर्नकी एसोसियेट्स के नाम की सिफारिश सी०पी०एम० सांसद और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अमल दत्त ने की थी। अमल बाबू ज्योति बसु के भांजे हैं।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि कमल बाबू के अनुसार अमल बाबू के अनुरोध पर ही एच० के० सेन टर्नकी एसोसियेट्स को यह काम दिया गया। अमल दत्त ने मेयर के इस कथन का विरोध किया है। अमल दत्त के विरुद्ध कमल बसु के इस वक्तव्य की प्रतिक्रिया के बारे में पूछने पर अमल बाबू ने बताया कि एच०के० सेन को काम देने के बारे में मैंने किसी तरह की सिफारिश नहीं की। एच०के० सेन को मैं जरूर जानता हूं।

लेकिन मेयर इस मामले में अपने कथन से जौ भर भी पीछे नहीं हटे थे। अमल बाबू ने जब इस संबंध में पूछा तो मेयर ने बताया कि मैं अखबार नहीं देखता। अमल बाबू के कथनानुसार उनके बारे में मेयर का आरोप निराधार है। और इस तरह की बातों से उनकी छवि धूमिल हुई है। लेकिन मेयर कमल बाबू ने अपना आरोप वापस लेने का प्रयास तक नहीं किया और १३ जुलाई, १९८७ को शाम को चार बजकर, दस मिनट हुए थे। सारे कलकत्तावासियों के कौतूहल को शांत करते हुए कलकत्ता नगर निगम के मेयर कमल बसु ने आखिर यह बयान दे ही दिया, "हमने कोई गलती नहीं की। निजी विकासकर्ताओं को कलकत्ते के विकास का कार्यभार सौंपकर हमने ठीक किया है। हम लोगों में उतना सामर्थ्य नहीं है। व्यवसायियों के सौजन्य से यदि इस नगर को पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, तो बुरा क्या? हम जानते हैं कि प्राइवेट निर्माणकर्ता काले धन का लेन-देन करते हैं। लेकिन हम भी तो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए यह कोई गलत काम नहीं है।" कमल बाबू जब ये बातें कह रहे थे, तब वह बड़े ही धीर-स्थिर लग रहे थे। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनको यह आभास हो कि तमाम कलकत्तावासी उनके इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। हमेशा की तरह शांत हंसी बिखेरते हुए कमल बाबू कहते गये, "व्यवसायियों के बारे में सामान्य लोगों में अनेक गलत धारणाएं हैं। भारत सरकार भी विभिन्न अवसरों पर उद्योगपतियों से सहायता लेती है। रडन स्क्वैयर के मामले में हमने अगर उनसे सहायता मांगी है, तो वह अनुचित नहीं है।"

कांग्रेसी विधायक सुव्रत मुखर्जी भी धीरे-धीरे मैदान में आ गये हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मेयर का घेराव करूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेसी कौंसिलरों का सवाल है कि गैरबंगाली व्यवसायियों को गले लगाने के लिए नगर निगम के कानून क्यों तोड़े गये? अमल दत्त को क्या यह पता नहीं था कि अरुण बाजोरिया करोड़ों रुपए के काले धन के मालिक हैं? या अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ने के लिए महोदय ने यह सब नाटक किया?

फिर भी यह सोचने पर बड़ा आश्चर्य लगता है कि कभी इसी वाम मोर्चा सरकार ने पूंजीपतियों के विरुद्ध कितना विष-वमन किया था? पूंजीपतियों को इन वामपंथियों ने 'वर्ग-शत्रु' करार दिया था। लेकिन आज की स्थिति में इन्हीं वामपंथियों ने उन्हीं बुर्जुआ लोगों से हाथ मिलाया है। अभी हमारे मार्क्सवादी मुख्यमंत्री की बिड़ला ने प्रशंसा की है। क्रीड़ा मंत्री सुभाष चक्रवर्ती ने एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को 'पद्मश्री' देने की सिफारिश की थी। एक कांग्रेसी विधायक का कहना है कि ऐसी उदारता से मार्क्सवादी धन तो एकत्र कर सकते हैं, लेकिन जनता में उनकी साख भी गिरनी शुरू हो गयी है, जिसका खमियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है।

—मणिशंकर देवनाथ

गैस पीड़ितों पर दोहरी मार

उग्र विरोध : गैस पीड़ित महिला उद्यमियों का भोपाल में धरना

विश्व की अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक गैस दुर्घटना के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किये, लेकिन अफसरशाही और स्वयंसेवी संस्थाएं आफत के मारे इन गैसपीड़ितों का शोषण करने से भी बाज नहीं आयीं। गैसपीड़ित महिलाएं इस शोषण के खिलाफ सड़कों पर निकल आयी हैं और लाखों रुपए के गोलमाल के प्रकरण सामने आने लगे हैं। गैसपीड़ितों के लिए आहार, उपचार, रोजगार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार का उद्‌घाटन कर रहे हैं **सुधीर सक्सेना**

भयावह दुर्घटनाएं अपने पीछे सदैव मनश्ताप, रोग-शोक और दुःस्वप्नों का सिलसिला छोड़ जाती हैं। विश्व की अब तक की सबसे बड़ी और भयावह औद्योगिक दुर्घटना के शिकार हजारों लोग आज भी इस त्रासदी की विभीषिका से उबर नहीं सके हैं। गैसपीड़ितों के पुनर्वास का काम आज भी अधर में लटका हुआ है। सरकार इस मद में करोड़ों रुपए फूंक चुकी है, मगर अफसरशाही के कारण नतीजा 'ढाक के तीन पात' रहा है। भोपाल के गैस पीड़ितों का दोहरा दुर्भाग्य यह है कि उन्हें अफसरशाही और छुटभैये नेताओं के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी छला है। सचाई यह है कि अफसर मुख्यमंत्री की फजीहत करने पर तुले हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं ढकोसला खड़ाकर अपनी जेबें भरने में। ऐसे में गैसपीड़ितों का भला कैसे हो? नेक-नीयत मगर प्रशासनिक तौर पर दुर्बल मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा करें, तो क्या करें? दोष उनका नहीं, उनके चरित्र व स्वभाव का है। वह पहाड़ सी घोषणाएं कर डालते हैं और याचक के कंधे पर गठरी भर आश्वासन बांध देते हैं, परंतु जब अमल और नतीजे पर बात पहुंचती है, तो पहाड़ दरका हुआ नजर आता है और व्यक्ति के हिस्से चुटकीभर मदद आ जाये, तो उसकी खुशनसीबी। भ्रष्ट प्रशासन तंत्र के कलपुर्जे कब और कैसे चलते हैं, यह अब लोगों से छिपा नहीं है। गैस-पीड़ितों के पुनर्वास, रोजगार, उपचार और कल्याण की कथा के पन्ने पलटें, तो यह दुर्भाग्यजनक तथ्य भी उभरता है कि शनैः शनैः अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं 'मठों' की शक्ल अख्तियार करती जा रही हैं।

थाने का घेराव

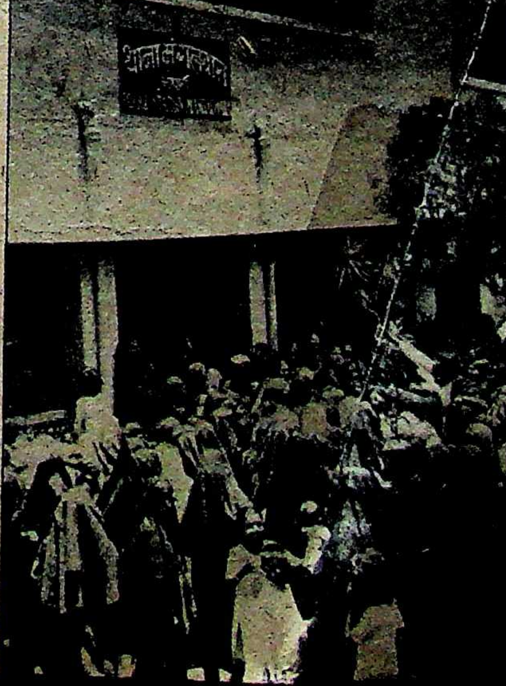

महिलाएं सड़क पर : इस वर्ष २३, २७ और ३० जनवरी और फिर १० एवं २३ फरवरी को गैसपीड़ित महिलाओं ने भोपाल गैसपीड़ित महिला उद्योग संगठन के बैनर तले भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन किये और अधिकारियों को ज्ञापन दिये। महिलाओं की मुख्य मांग थी कि उन्हें रोजगार मुहैया किया जाये, ताकि वे अपने व अपने बाल-बच्चों के लिए दो जून की रोटी जुटा सकें। जब इससे शासन के कान पर जूं नहीं रेंगी, तो २३ फरवरी से १२ मार्च तक श्यामला हिल पर मुख्यमंत्री के बंगले

के सामने भूख हड़ताल की गयी। १२ मार्च को उनकी मुख्यमंत्री श्री वोरा से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान श्री वोरा ने संगठन को आश्वस्त किया कि संगठन की सभी बेसहारा और बेरोजगार औरतों को काम दिया जायेगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कायदे से दीन-दुखियारी औरतों को काम मिल जाना चाहिए था। सरकार की इच्छा व संकल्प के बाद इसमें कोई रुकावट नहीं, मगर अफ़सरशाही की अड़ंगेबाजी और कुछ छुटभैये नेताओं के स्वार्थ ने मुख्यमंत्री के वायदे की धज्जियां उड़ा दीं।

इस साल जनवरी माह में भोपाल में भोपाल गैस-पीड़ित महिला उद्योग संगठन की नींव पड़ी और आज दो हजार से भी अधिक मजलूम औरतें इस संगठन से जुड़ी हुई हैं। इस संगठन की नींव डालने और उसे मजबूत बनाने का श्रेय जाता है, अब्दुल जब्बार खां नामक व्यक्ति को, जिसका पूरा परिवार मय उसके गैस-त्रासदी का शिकार हुआ है। प्रारंभ में संगठन में महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन ज्यों-ज्यों गैसपीड़ितों के लिए निर्मित वर्कशेड बंद होते गये, बेरोजगार महिलाएं संगठन की 'कैनोपी' के तले एकत्र होती गयीं। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की वायदा-खिलाफी को लेकर संगठन की औरतों, जिनमें बाल बच्चेदार बुर्काधारी महिलाओं की अधिकता थी ने २८ मई को विधानसभा के समक्ष गिरफ्तारियां दीं। रोज़गार की मांग को लेकर १० जून को ज्ञापन देने के बाद नौ, तेरह व चौदह जुलाई को बड़ी संख्या में औरतों ने पुनः गिरफ्तारियां दीं। इस दरम्यान दो दर्दनाक घटनाएं भी घटीं। २३ जनवरी को प्रदर्शन के दौरान पांच बच्चों की मां चालीस वर्षीया हमीदा बी गश खाकर गिर पड़ी। उसे खान शाकिर अली चिकित्सालय में परीक्षण के बाद हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां २६ जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। इसी प्रकार १० फरवरी को एक महिला को प्रदर्शन के दौरान गर्भपात हो गया।

अफसरशाही : सरकार गैसपीड़ित महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर वाकई चिंतित है इसका परिचय देते हुए मध्य प्रदेश शासन ने ५० वर्कशेड बनाने का फैसला किया। अधिकारियों की अरुचि के कारण पचास के लक्ष्य के विपरीत चालीस ही शेड बन सके, जिन्हें प्रति शेड १.१० लाख रुपए की लागत से राजधानी परियोजना ने बनवाया। इन शेडों का निर्माण भी मुख्यमंत्री श्री वोरा की व्यक्तिगत रुचि और दौड़धूप के कारण संभव हो सका। इनका निर्माण गैसपीड़ित महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से किया गया था, लेकिन इनमें से आधे से अधिक यानी बाईस शेड मई बीतते-न-बीतते बंद हो गये। और जो बंद नहीं हुए, उन्हें कुप्रबंध, अनियमितताओं और शोषण के व्यालजाल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज हालत यह है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपे गये बाईस वर्कशेडों में से १८ बंद हैं और सिर्फ चार चालू हैं। रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय का दायित्व जिला कलेक्टरेट की पुनर्वास शाखा को सौंपा गया था। उसने प्रशिक्षण देने के लिए सुदूर अहमदाबाद की एक संस्था इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स को बुलाया। इसी प्रकार गैसपीड़ितों के पुनर्वास का प्रारूप चार लाख रुपए देकर 'जिडको' से तैयार कराया गया। जिडको (गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंसल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन) को न्यौतने का प्रसंग अखरता इसलिए है, क्योंकि एम०पी० कॉन (मध्य प्रदेश कन्सल्टेंसी आर्गेनाइजेशन) इसी काम को केवल डेढ़ लाख रुपए में करने को तैयार था। रोजगार व प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय का दायित्व बस्तर से भोपाल आये युवा अतिरिक्त कलेक्टर प्रवेश शर्मा के कंधों पर पड़ा, किंतु वह इतनी महती जिम्मेदारी को अपेक्षित सूझबूझ और सफलता से कर नहीं सके। उनके जाने के बाद यह जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश स्नेहलता श्रीवास्तव को वहन करनी पड़ी।

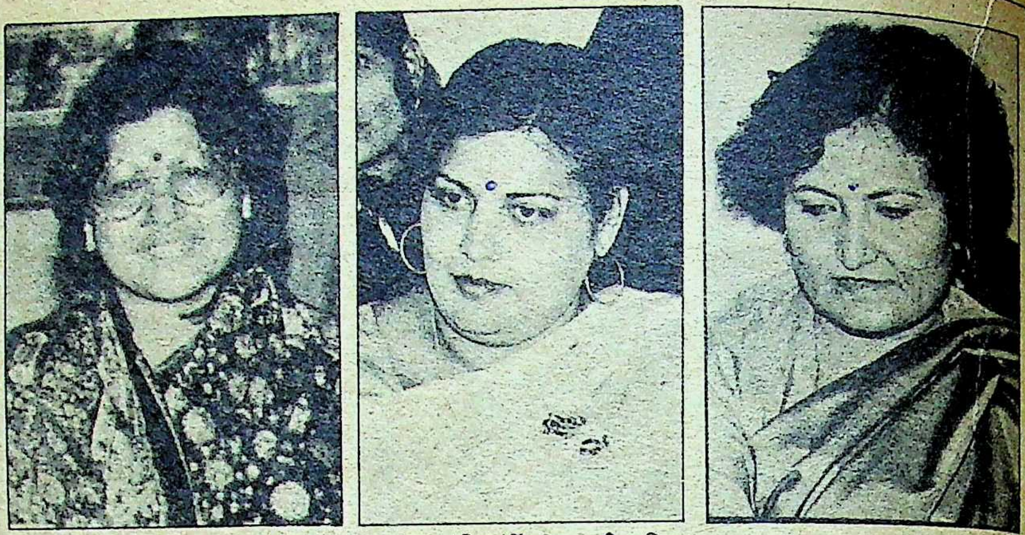
गैस पीड़ितों का शोषण : बायें से इंदिरा आयंगर, इंदिरा सिंहल, रूही मलिक

स्वावलम्बन : वर्कशेडों को चालू होने के कुछ समय बाद से ही अनियमितताओं ने अपनी चपेट में ले लिया था। असंतोष, विवाद, निहित स्वार्थों की लड़ाई और ज्यादा-से-ज्यादा कमाई के लोभ की परिणति वर्कशेडों के बंद होने में हुई। सबसे पहले महिला चेतना मंच का सबसे बड़ा सिलाई केंद्र 'स्वावलंबन' बंद हुआ, इसके बाद आधे से अधिक वर्कशेड बंद कर दिये गये। जब गैस-पीड़ित महिला उद्योग संगठन की महिलाओं ने अब्दुल जब्बार खां के नेतृत्व में लंबा आंदोलन छेड़ा, तब कहीं जाकर कुछ शेड चालू हुए, अन्यथा अब तक सब-के-सब शेड बंद हो चुके होते।

अकेले 'स्वावलंबन' के बंद होने से करीब डेढ़ हजार महिलाएं बेरोजगार होकर सड़क पर आ गयीं और उन्होंने भारत टाकीज के पास धरने का धारावाहिक कार्यक्रम प्रारंभ किया। 'स्वावलंबन' के बंद होने का औचित्य इसलिए पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि यह महिला चेतना मंच द्वारा संचालित है, जिसकी कर्ताधर्ता मध्यप्रदेश शासन में प्रमुख सचिव और अत्यंत शक्तिशाली आई०ए०एस० अधिकारी श्रीमती निर्मला बुच हैं। सरकार ने उन्हें विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, २० सूत्री क्रियान्वयन और समाज-कल्याण का प्रशासनिक दायित्व सौंप रखा है। वल्लभ भवन में उनकी तूती बोलती है। कहते तो यहां तक हैं कि उनके विभागों में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक खड़कने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय में संचालक पद पर युवा आई०ए०एस० अंशु वैश को पदस्थ करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अशासकीय रूप से संचालित श्रीमती बुच की संस्था महिला चेतना मंच को ४ लाख रुपए का वार्षिक शासकीय अनुदान प्राप्त होता है। उनकी एक अन्य संस्था आश्रम को २५ हजार रुपए का अनुदान स्वीकृत है। श्रीमती बुच इसके अलावा मंजरी पुस्तकालय, अंकुर स्कूल और कल्याणी (महिला छात्रावास) से भी संबद्ध हैं। 'स्वावलंबन' ने पिछले कुछ सालों में सिलाई के बड़े आदेशों के जरिए लाखों रुपए की कमाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंच को १९८५-८६ में साढ़े चार लाख सेटों की सिलाई का आदेश मिला था। एक सेट तैयार करने में तकरीबन साढ़े सत्रह रुपए की लागत आयी और इन्हें प्रति सेट २६ रुपए में सप्लाई किया गया। प्रति सेट आठ रुपए का भी मुनाफा गिनें, तो मंच को इस एकमेव आर्डर से करीब ३४ लाख रुपए का लाभ हुआ। बताते हैं कि मंच को इन्हीं दिनों 'पढ़ाओ-कमाओ' योजना के तहत दस लाख का एक और आदेश मिला था। 'स्वावलंबन' केंद्र के बंद होने के बाद महिला उद्योग संगठन ने मांग की कि सरकार स्वावलंबन को अपने हाथ में ले ले और उसे चालू करे। संगठन के संयोजक जब्बार खां और अध्यक्ष राबिया सुल्ताना ने इस बारे में मुख्यमंत्री श्री वोरा से कई बार चर्चा की और उन्हें ज्ञापन भी दिये, मगर श्रीमती बुच के शक्तिशाली आई०ए०एस० होने के नाते सरकार 'स्वावलंबन' पर हाथ नहीं डाल सकी। २६ फरवरी को श्री वोरा को दिये अपने ज्ञापन में कहा गया कि 'स्वावलंबन' की गैसपीड़ित महिलाओं से मुंह फेर लेने के कारण महिलाओं को गर्दिश का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि कई शासकीय व अर्ध-शासकीय विभागों, प्रमुखतः शिक्षा विभाग, डाक तार विभाग एवं महालेखाकार का कार्य अभी भी 'स्वावलंबन' के पास है, जिन्हें वह सीधे गैसपीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराने के बजाय स्थानीय राजनीति में दखल रखनेवाले नेताओं-नेत्रियों को उपलब्ध करा रही है। ज्ञापन में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, वे हैं : श्रीमती रुक्मणी भार्गव, मुकीत मलिक एवं श्रीमती रूही मलिक, फखरुद्दीन अली अहमद, राजकुमारी शर्मा, राजकुमारी जौहर, श्रीमती इंदिरा सिंहल और महिला चेतना मंच द्वारा संचालित संस्था मंजरी।

इस ज्ञापन में और तदंतर 'माया' संवाददाता से चर्चा में जब्बार खां ने आरोप लगाया कि उपरोक्त

संस्थाएं अपनी संस्थाओं में कम मजदूरी का भुगतानकर गैसपीड़ित महिलाओं का आर्थिक शोषण कर रही हैं। जब्बार खां ने ऐसे कुछ हलफनामे भी दिखाये, जिनमें औरतों ने उक्त व्यक्तियों के हाथों अपने आर्थिक शोषण की पुष्टि की है। समीना वहीद आयु २० साल पत्नी अ० वहीद, शाहिदा बी आयु ३० साल पत्नी रशीद खां, ताहिरा बी आयु ३२ वर्ष पत्नी मो० हारुन, अनवरी बेगम आयु ३० वर्ष पत्नी शौकत अली, हाजरा बी पुत्री शरीफ बेग. रूबीया आयु २० वर्ष पुत्री रफीक ने संयुक्त शपथपत्र में कहा कि वे सुल्ताने-हिन्द एजुकेशनल सोसायटी, जिसकी संचालिका रूही मलिक हैं, के यहां सिलाई का काम करती थीं, किंतु रूही मलिक ने उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी, उलटे उन्हें सताया। इसी प्रकार, श्रीमती नाजमा बी (४०) विधवा अबरार खां, जलीला बी (४८) विधवा बहादुर खां, असमा बी (२०) पत्नी अनीस बेग, अफसर जहां (३०) पत्नी हकरामुद्दीन, श्रीमती कमर बी (५०) पत्नी हफीज खां, श्रीमती रजिया बेगम विधवा नूर मोहम्मद ने श्रीमती इंदिरा सिंहल के खिलाफ और जाहिरा बी पत्नी जाहिद हुसैन, रईसा बी पत्नी इनायत खां, सईदा बी पत्नी इसहाक मोहम्मद और रईस बी पत्नी जमालुद्दीन ने सेवा संस्थान की रुक्मणि भार्गव और अफरोजजहां पत्नी हकीमुद्दीन, जाहिदा बी पत्नी खलील अहमद और समीना पत्नी इकबाल अहमद ने प्रियदर्शिनी की संचालिका श्रीमती इंदिरा आयंगर के खिलाफ मजदूरी न देने का आरोप हलफनामा देकर लगाया। इसी आशय के हलफनामे मुख्यमंत्री को दिये गये ज्ञापन में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों के बारे में भी देखने को मिले।

'नोडल एजेंसी' की दुर्गति : मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम उन सरकारी उपक्रमों में से एक है, जिन्होंने गैसपीड़ितो के पुनर्वास में प्रारंभ से सक्रिय रुचि ली। निगम के अध्यक्ष इन दिनों माणक अग्रवाल हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के काफी नजदीक माने जाते हैं। इसके बाद भी निगम को अफसरों की अड़ंगेबाजी और आला-अफसरों के दबाव का सामना करना पड़ा। गैसपीड़ितों के रोजगार व प्रशिक्षण के लिए निगम ने भोपाल में काली परेड व चांदबड़ इलाके में फाइल पैड, पेपर कन्वर्शन, दोना-पत्तल, सिलाई केंद्र व सिलाई प्रशिक्षण, होजयरी, बुनाई, वस्त्रनिर्माण, बढ़ईगीरी आदि की इकाइयां प्रारंभ कीं। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने फरवरी, १९८७ में गैस राहत योजना के लिए निगम को ३४ लाख रुपए देने का वायदा किया। इस आशय की फाइल 'मूव' हो चुकी थी कि निगम के प्रबंध संचालक जी० वेंकन्ना को अचानक उक्त पद से विदा होना पड़ा। श्री वेंकन्ना बल्लभ भवन में सक्रिय उस तगड़ी 'आंध्रा लाबी' के सदस्य माने जाते थे, जिसके दो अन्य सदस्य थे—वित्त सचिव शिवरमण और वरिष्ठ आई०ए०एस० जी० जगतपति। राज्य उद्योग निगम के कूचे से श्री वेंकन्ना की आकस्मिक विदाई को तिकड़ी ने गंभीरता से लिया और तिकड़ी के सदस्य श्री शिवरमण ने ३४ लाख रुपए से संबंधित प्रस्ताव को वित्तसचिव की हैसियत से रद्द कर दिया। नतीजतन, निगम को ३४ लाख रुपए की रकम मिलते-मिलते रह गयी। बताते हैं कि इस प्रस्ताव में गैस राहत आयुक्त व पूर्व संभागायुक्त श्री सत्यम की विशेष रुचि थी, लेकिन श्री शिवरमण ने उनकी इच्छा की भी परवाह नहीं की। बहरहाल, इससे नुकसान निगम का कम, गैसपीड़ितों का अधिक हुआ, क्योंकि यह राशि गैसपीड़ितों के पुनर्वास पर ही व्यय होनी थी।

गैसपीड़ितों के पुनर्वास के प्रति अफसरों की बेरुखी का सिलसिला यहीं खतम नहीं होता। २७ मार्च, १९८७ को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने पत्र क्र० २४७२/१४१२/११/अ के जरिये मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम को 'नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया कि गणवेशों की सिलाई का काम गैसपीड़ित महिलाओं को दिया जाये और इसके लिए निगम कलेक्टरेट से गैसपीड़ित महिलाओं की सूची प्राप्त करे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री वोरा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि वह गणवेशों की सिलाई का काम नोडल एजेंसी को प्रदान करे, लेकिन शिक्षा विभाग के नकचढ़े अधिकारियों ने इस आदेश को उठाकर ताक पर रख दिया, जबकि विभिन्न स्कूल-गणवेश के लिए करीब १४ लाख रुपए बतौर अग्रिम दे चुके थे। राज्य उद्योग निगम ने गैसपीड़ित महिलाओं की सूची देने का अतिरिक्त कलेक्टर से बारंबार अनुरोध किया। महिला उद्योग संगठन ने भी इस ओर श्री वोरा का ध्यान आकृष्ट किया, मगर सूची निगम को न मिलनी थी न मिली। निगम ने यह भी मांग की कि 'स्वावलंबन' का बंद पड़ा वर्कशेड उसे दे दिया जाये, किंतु यह भी नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, निगम को भारत टाकीज के समीप खुले में अपना काम चालू करना पड़ा।

सत्ता का दंभ : श्रीमती निर्मला बुच

महिला उद्योग संगठन ने मुख्यमंत्री से हर बार भेंट में और ज्ञापनों के जरिये लगातार यह मांग की कि सिलाई, बुनाई आदि का काम किसी बिचौलिया संस्था को कतई न दिया जाये, जो गैसपीड़ित दीन-दुखियारी औरतों का शोषण करती हैं। श्री जब्बार ने निगम के चेयरमैन श्री अग्रवाल तक भी यह बात पहुंचाई, लेकिन निगम को महिला कामगारों की सूची बारंबार अनुरोध करने पर भी न देनेवाले अति० कलेक्टर ने उन संस्थाओं व व्यक्तियों को काम देने की अनुशंसा कर डाली, जिनके खिलाफ गैसपीड़ित महिलाओं ने शपथ-पत्र देकर शिकायतें की थीं। परिणामस्वरूप, शासन ने रुक्मणि भार्गव की संस्था सेवा संस्थान' फखरुद्दीन अली अहमद की 'आदर्श होजरी' श्रीमती रूही मलिक की 'सुल्ताने हिन्द एजुकेशनल सोसायटी' और 'मुस्लिम कल्याण केंद्र' को सीधे काम दे दिया। जानकार सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त जिलाधीश ने 'नूतन एजुकेशनल सोसायटी' व श्रीमती निर्मला बुच की संस्था 'महिला सेवा समिति' को भी काम देने की सिफारिश की है। खोजखबर के दौरान यह भी पता चला कि आला-अफसर के वरदहस्त के कारण एक संस्था ने गैसपीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रदत्त धन से कंप्यूटर तक खरीद लिया है, छोटी-मोटी चीजों की क्या बिसात?

अब्दुल जब्बार गैसपीड़ित महिलाओं के हक में न्याय की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, परंतु उनका अनुभव अच्छा नहीं है। शुरू में धमकियों के बाद मार्च में उन पर गुंडों ने हमला किया। जिन्होंने उन पर हमला किया, उनसे उनकी कोई अदावत नहीं थी। जाहिर है कि उन पर उन लोगों ने भाड़े के गुंडों से हमला कराया, जिनके हितों को उनके नेतृत्व में चल रहे महिलाओं के आंदोलन से चोट पहुंचती है। एक बार उन्हें फर्जी शिकायत पर पुलिस ने भी धरपकड़ा, जिस पर महिलाओं ने थाने का घेराव कर उन्हें छुड़ाया।

श्री जब्बार का कहना है कि अगर वर्कशेडों को स्थायी उद्योगों में परिवर्तित कर दिया जाये, तो करीब दो हजार औरतों को साल भर रोजगार मिलेगा और करीब दस हजार लोगों का पेट पलेगा। पीड़ितों के पुनर्वास के नाम पर ढोल में पोल और खोटे की जानकारी शासन के छोटे-बड़े अफसरों को भी है और राजनेताओं को भी, लेकिन हुआ यह है कि व्यावसायिकता के इस युग में निजी स्वार्थ हजारों गैसपीड़ितों के हितों पर हावी हो गये हैं। राजनीति में दखल रखनेवाले कुछ लोग स्वयंसेवी संस्थाओं की आड़ में मुनाफा पीट रहे हैं। अपने ही दर्प और दंभ में डूबी नौकरशाही का तो कहना ही क्या? नौकरशाही के रवैये और सलूक से सर्वाधिक किरकिरी और थुक्का-फजीहत यदि किसी की हो रही है, तो वह हैं, मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा। प्राकृतिक आपदाओं से जूझने को अभिशप्त श्री वोरा को संभवतः यह पता होगा कि गैसपीड़ितों के लिए आहार, उपचार, रोजगार, प्रशिक्षण और पुनर्वास आदि के नाम पर अब तक जो करोड़ों रुपए की राशि खर्च हुई है, उसमें से 'आटा' तो निहित स्वार्थों की जेब में गया है और वास्तविक गैसपीड़ितों के हाथ सिर्फ मुट्ठीभर चोकर लगा है। ■

छाया : बिम्ब स्टूडियो

मध्यप्रदेश यात्रा

पांच दिन का मनमोहक आकर्षण

विभिन्न मनमोहक रूपों वाले प्रदेश की ओर चलें,
जहाँ नदियों के किनारे मंदिर बने हैं, हवाओं के
झोंकों में पले किले हैं और सुगंधित फूलों से
सजे पुराने स्मारक हैं।
यह चार दिन का मनमोहक आकर्षण है।
मध्यप्रदेश – आप इसे देखकर
आनंद विभोर हो उठेंगे।

हमारी यात्रा में शामिल हैं
देहली - ग्वालियर - ओरछा - खजुराहो - शिवपुरी - ग्वालियर - देहली

यात्रा अवधि
4 रात 3 दिन
(रेल यात्रा का समय अलग)

किराया
वयस्क : 899/– रुपए प्रति व्यक्ति
सिंगल रूम : 949/– रुपए प्रति व्यक्ति

12 साल से कम आयु के बच्चे
(अलग पलंग सहित) : 815/– रुपए

12 साल से कम आयु के बच्चे
(अलग पलंग के बिना) : 715/– रुपए

इस भ्रमण में शामिल हैं
देहली से ग्वालियर और ग्वालियर से देहली का दूसरी श्रेणी का किराया, ठहरने व खाने का प्रबंध, राज्य में कोच से आने-जाने की व्यवस्था, सब स्थानों में प्रवेश शुल्क, गाईड और सहायक की सेवाएं।

प्रस्थान
प्रत्येक शुक्रवार को।

जल्दी करें!
तत्काल आरक्षण करवाएं!

मध्य प्रदेश
भारत का हृदय

सूचना और आरक्षण के लिए सम्पर्क करें
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
204 - 205, दूसरी मंजिल, होटल कनिष्का शॉपिंग प्लाज़ा 19, अशोक रोड नई देहली - 110 001
फोन : 351187 टैलेक्स : 031 - 63417 एम पी टी - इन.

पर्यटन विकास निगम

बस, केवल तीन करोड़ रुपए !

अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी के पत्रकार पिता तरुण कुमार भादुड़ी को १९७८ में स्थापित मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का १९८५ में जब अध्यक्ष बनाया गया था, तो उम्मीद थी कि वह अनियमितताओं, फिजूलखर्ची और कुप्रबंध को दूरकर निगम को घाटे के दलदल से निकाल ले जायेंगे, लेकिन अब स्वयं उन्हीं पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि अपनी फिजूलखर्ची और कुप्रबंध से उन्होंने निगम का घाटा तीन करोड़ तक पहुंचा दिया है ? असलियत की जांच-पड़ताल

सुधीर सक्सेना द्वारा :

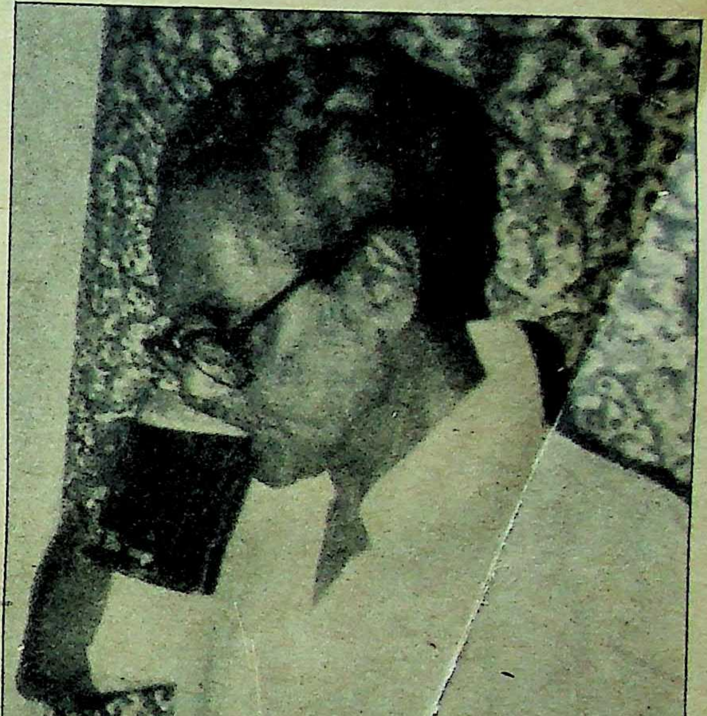

संबंधों का सुख : म०प्र० पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तरुण कुमार भादुड़ी का चर्चित चित्र

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसा शासकीय उपक्रम है, जिसने सन् १९७८ में अपनी स्थापना के बाद से आज तक कभी लाभ का मुंह नहीं देखा। मध्यप्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि पर्यटन निगम पूरे प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का व्यावहारिक ढांचा खड़ाकर सैलानियों की वाह-वाही लूटता और अपने पैरों पर खड़ा होकर जल्द-से-जल्द घाटे से मुक्त हो लेता, मगर ऐसा हो न सका। कारण यह कि निगम प्रारंभ से ही अनियमितताओं, फिजूलखर्ची और कुप्रबंध का शिकार रहा है। कुछ साल पहले तक पर्यटनमंत्री निगम का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने इस परंपरा को यकबयक तिलांजलि दे दी। अध्यक्ष पद पर नये व्यक्ति की नियुक्ति से और कुछ हुआ हो या नहीं, किंतु निगम पर बोझ अवश्य बढ़ गया और जल्दी ही अध्यक्ष की आदतों के कारण निगम सुर्खियों में आ गया। रही-सही कसर नये प्रबंध संचालक के आगमन ने पूरी कर दी। नये प्रबंध संचालक पर तानाशाही, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और तुगलकी फरमान जारी करने के आरोप लगे। निगम के कर्मचारियों ने न केवल परचेबाजी और हड़ताल की, वरन वे जाकर लोकायुक्त के यहां भी दस्तक दे आये।

अध्यक्ष सुर्खियों में : तरुण कुमार भादुड़ी मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की कलम से बने किसी शासकीय उपक्रम के पहले चेयरमैन हैं। श्री वोरा मार्च १९८५ में मुख्यमंत्री बने और मई १९८५ में उन्होंने फिल्मी दुनिया के सुपर स्टार और तत्कालीन सांसद अमिताभ बच्चन के श्वसुर श्री भादुड़ी को पर्यटन निगम का अध्यक्ष बना दिया। इस कारण संकेत भी किया जाता है कि श्री भादुड़ी जो कुछ ही समय पहले सक्रिय पत्रकारिता से निवृत्त हुए थे, की इस पद पर नियुक्ति में उनकी बिटिया जया बच्चन की अहम भूमिका रही है। बताते हैं कि जया ने श्रीमती सोनिया गांधी से कहा और सोनिया ने माखनलाल फोतेदार से। दिल्ली से श्री वोरा के लिए श्री फोतेदार का फोन आने की देर थी कि श्री वोरा ने तामील में देर नहीं की।

'स्टेट्समैन' के संवाददाता रह चुके श्री भादुड़ी ने अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों बाद लखनऊ से अपने कुछ पत्रकार मित्रों को निगम के खर्चे पर भोपाल बुलाया और उन्हें प्राकृतिक वैभव से संपन्न मध्यप्रदेश की सैर करायी। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है कि इन पत्रकारों ने लखनऊ लौटने के बाद क्या वाकई ऐसा कुछ किया या लिखा, जिससे म०प्र० में पर्यटन या पर्यटन निगम को कोई लाभ पहुंचा हो। इसी क्रम में अध्यक्ष बनने के बाद श्री भादुड़ी गोवा गये। उनकी गोवा यात्रा पर निगम ने करीब दस हजार रुपए खर्च किये। कथित तौर पर श्री भादुड़ी गोवा पर्यटन सुविधाओं के अध्ययन के लिए गये थे, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि उनके गोवा जाने का प्रयोजन वहां के सुरम्य वातावरण में अपने विवाह की ४१वीं सालगिरह मनाना था। इस बात को इससे बल मिलता है कि समुद्र तट पर बसे गोवा में पर्यटन सुविधाओं का मध्य प्रदेश की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है।

गोवा यात्रा की भांति श्री भादुड़ी की कलकत्ता और भेड़ाघाट (जबलपुर) यात्रा भी अखबारों की सुर्खियों में रही। श्री भादुड़ी के खिलाफ निगम

तुगलकी लहजा : अजमानी

तरुण कुमार भादुड़ी मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की कलम से बने किसी शासकीय उपक्रम के पहले चेयरमैन हैं। श्री वोरा मार्च १९८५ में मुख्यमंत्री बने और मई १९८५ में उन्होंने फिल्मी दुनिया के सुपर स्टार और तत्कालीन सांसद अमिताभ बच्चन के श्वसुर श्री भादुड़ी को पर्यटन निगम का अध्यक्ष बना दिया। इस कारण संकेत भी किया जाता है कि श्री भादुड़ी जो कुछ ही समय पहले सक्रिय पत्रकारिता से निवृत्त हुए थे, की इस पद पर नियुक्ति में उनकी बिटिया जया बच्चन की अहम भूमिका रही है।

के कर्मचारियों ने जो परचेबाजी की, उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिये और प्रधानमंत्री को शिकायतनामा भेजा, उसमें कहा गया है कि श्री भादुड़ी की कलकत्ता यात्रा पर लगभग २५ हजार रुपए खर्च हुए। श्री भादुड़ी की भेड़ाघाट यात्रा इसलिए चर्चा का विषय रही, क्योंकि २७ फरवरी, १९८६ को वाउचर क्रमांक-४२९ से निगम के होटल 'मार्बल राक्स इन' ने अध्यक्ष के लिए अपने पैसे से मैक्डावल की बोतल खरीदी। निगम के जबलपुर दफ्तर के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बाद में 'राक्स इन' के प्रबंधक को लिखा कि अध्यक्ष के लिए खरीदी गयी मैक्डावल प्रीमियम की बोतल में बचे छह पेग आगे के लिए सुरक्षित रखे जायें।

सैर-सपाटे और खानपान पर खर्च के अलावा, श्री भादुड़ी के घर पर आयोजित 'होली मिलन' समारोह पर भी जानकार सूत्रों के अनुसार, निगम ने एक बार तीन हजार रुपए खर्च किये। ये तीन हजार रुपये गुलाल, अबीर के अतिरिक्त स्वाभाविक तौर पर मेहमाननवाजी के लिए आयी दारू पर भी खर्च हुए। मध्य प्रदेश शासन ने घर की साज-सज्जा के लिए १५ हजार रुपए की अनुमति दी थी, किंतु श्री भादुड़ी के घर को उनके मनमाफिक बनाने और सजाने-संवारने में निगम को अपने खाते से १५ हजार रुपए अतिरिक्त व्यय करने पड़े। इसके अलावा, श्री भादुड़ी ने निगम की नर्सरी को भी अपने आवास पर 'शिफ्ट' करवा लिया। शानो-शौकत के शौकीन श्री भादुड़ी ने पदभार-संभालने के बाद एक और काम किया। उन्होंने अपने कमरे की साज-सज्जा पर ७५ हजार रुपए खर्च किये। कार्यालय की अंतर्सज्जा का काम उन्होंने किसी और को नहीं, वरन अपने भांजे आशीष भट्टाचार्य को दिया। बताते हैं इसके लिए टेंडर भी नहीं मांगे गये।

निगम कर्मचारियों ने अध्यक्ष के विरुद्ध जो शिकायतनामा ऊपर तक भेजा है, उसमें कुछ और बातों का भी उल्लेख है। आरोप-पत्र में कहा गया है कि एल०एम० पंत और हर्ष वर्मा नामक दो अधिकारी अध्यक्ष की चाकरी और जी-हुजूरी में लगे रहते हैं और उनके दम पर मातहत कर्मचारियों को आतंकित करते व धमकाते हैं। श्री पंत निगम में महाप्रबंधक, कार्मिक पद पर कार्यरत हैं और १२ मार्च, १९८६ से वह अध्यक्ष महोदय के विशेष सहायक भी हैं। उनके खिलाफ कुछ लोगों ने हलफनामा देकर शिकायतें की हैं। वह निगम में सात वर्ष प्रबंधक पद पर आसीन रहे और अब सेवामुक्त आई०पी० वालिया ने लोकायुक्त को दिये आवेदन में कहा है कि श्री पंत ने उनसे १० हजार रुपए की मांग की थी, जिसकी व्यवस्था वह नहीं कर सके। नतीजतन, उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया। श्री पंत के बारे में यह तथ्य प्रायः सभी समाचारपत्रों में छपा है कि उन्हें कुछ साल पहले घूस लेते पकड़ा गया था, लेकिन बाद में मामला रफा-दफा हो गया। आरोप-पत्र में एक और प्रसंग भी वर्णित है। सूचना सहायक पद पर कार्यरत एक महिला की वेतन वृद्धि कतिपय कारणों से रोक दी गयी थी। उसे कुछ दिनों बाद अकस्मात न केवल वेतन-वृद्धि दे दी गयी वरन अध्यक्ष महोदय ने उच्च वेतनमान देकर उसे अपने स्टाफ में नियुक्त कर लिया। इसके पीछे श्री पंत की सलाह का हाथ बताया जाता है।

अनियमितताएं : ऐसा लगता है कि निगम और अनियमितताओं का चोली-दामन का साथ है। अधिकारियों ने इसे पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने का जरिया कम और अपना चारागाह ज्यादा समझ लिया है। सन् १९८४ में तत्कालीन पर्यटनमंत्री कृष्णपाल सिंह ने कहा था कि प्रदेश में १०६० स्थान ऐसे हैं, जो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किये जा सकते हैं। यह आज भी शोध का विषय हो सकता है कि निगम ने इनमें से कितने स्थलों को विकसित किया ? इसमें संदेह नहीं कि प्राकृतिक वैभव से संपन्न मध्य प्रदेश में वह सब कुछ है, जो निगम के सक्षम व सुचारु रूप से काम करने की स्थिति में देश भर के सैलानियों को बड़ी संख्या में खींच कर ला सकता है और पर्यटन बारहमासी उद्योग के रूप में पनप सकता है। अनियमितताओं का ही परिणाम है कि निगम के पचमढ़ी, इंदौर और ग्वालियर के क्षेत्रीय

साक्षात्कार/ तरुण कुमार भादुड़ी

फिजूलखर्ची की नहीं, रोकी

फिल्मी दुनिया के सुपर सितारे अमिता बच्चन के श्वसुर और पत्रकार तरुण कुमार भादु के खिलाफ उनके विरोधियों ने एक शिकायतना तैयार करके प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भे था। इन आरोपों की जांच भी हुई थी। श्री भादु ने अपनी पहल पर इसे लोकायुक्त के पास भे दिया था। लोकायुक्त कार्यालय के सचिव श्री अ वाल ने उन्हें दिनांक २२ नवंबर, १९८६ को प के जरिये सूचना दी कि आरोपों को निराधा पाये जाने के कारण उनके खिलाफ मामला समा कर दिया गया है। होटल-मोटल आफिसर्स अ सिएशन की शिकायतों का हवाला देकर पर्यट एवं संस्कृति सचिव अशोक वाजपेयी ने अप अशासकीय पत्र क्रमांक ८८४/प-३३/८६ दिनां २ सितंबर, ८६ से सूचित किया कि आपके वि शिकायतें झूठी व निराधार पायी गयी हैं औ आपके खिलाफ झूठी शिकायतें करनेवाले क चारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवा करने के निर्देश प्रबंध संचालक को दिये गये हैं श्री भादुड़ी लोकायुक्त कार्यालय और श्री वा पेयी के पत्र को अपने 'पाक-दामन' होने का स या प्रमाणपत्र मानते हैं। प्रस्तुत है, मध्यप्रदे राज्य पर्यटन विकास निगम के गंगोत्री भव के चतुर्थ तल के सुसज्जित दफ्तर में श्री भादु से हुई बातचीत का सार संक्षेप :

कार्यालय बंद किये जा चुके हैं। सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने मई १९८६ में उच्च स्तर पर निगम की समीक्षा की। समीक्षा में मुख्य टिप्पणी यह थी कि निगम के संचालन, अमला एवं वाइन पर व्यय में कमी की जाये एवं निगम के व्यय के ऊपर नियंत्रण रखा जाये।

निगम में अपव्यय अकारण नहीं है। श्री वोरा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद निगमों की समीक्षा के दौरान पाया कि पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष पर काफी फालतू खर्च हो रहा है, लेकिन वह इसकी रोकथाम नहीं कर सके। निगम के उपाध्यक्ष खैरागढ़ रियासत के पूर्व महाराजा वीरेंद्र बहादुर सिह हैं। जब निगम का अस्तित्व भी नहीं था तब भी वह पर्यटन सलाहकार-बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। निगम बना तो वह उपाध्यक्ष बने और आज तक इस पद पर, महीनों निगम के दफ्तर न आने के बावजूद बरकरार हैं। उनके पुत्र शिवेंद्र बहादुर सिह राजनांदगांव से लोकसभा के सदस्य हैं और वह इस बात का डंका गाहे-बगाहे पीटते रहते हैं कि दून स्कूल में सहपाठी होने के नाते वह प्रधानमंत्री के अत्यंत करीब हैं। उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिह पर निगम सालाना औसतन दो लाख रुपए खर्च करता है और इस खर्च की उपयोगिता लोग आज तक नहीं बूझ सके हैं। नये अध्यक्ष के ऊपर अगस्त १९८५ से फरवरी १९८६ के बीच दो लाख रुपए का खर्च आया, तो उपाध्यक्ष ने भी अपनी शाहखर्ची का परिचय देते हुए फरवरी १९८५ से फरवरी १९८६ के बीच तीन लाख रुपए खर्च कर डाले। तत्कालीन प्रबंधसंचालक बी०के० बागची ने बड़े पैमाने पर दैनिक वेतन व अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर डाली। ऐसे में निगम के घाटे की रकम न बढ़े तो इसे दुनिया का नया आश्चर्य ही कहा जायेगा।

ऐसा लगता है कि निगम और अनियमितताओं का चोली-दामन का साथ है। अधिकारियों ने इसे पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने का जरिया कम और अपना चारागाह ज्यादा समझ लिया है। सन् १९८४ में तत्कालीन पर्यटनमंत्री कृष्णपाल सिंह ने कहा था कि प्रदेश में १०६० स्थान ऐसे हैं, जो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किये जा सकते हैं। यह आज भी शोध का विषय हो सकता है कि निगम ने इनमें से कितने स्थलों को विकसित किया।

नया मोड़ : श्री बागची पिछले साल तक निगम

माया : आपके खिलाफ दिल्ली तक भेजे गये आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि आपने अपने कार्यालय की साजसज्जा पर ७५ हजार रुपए व्यय किये और घर की साजसज्जा पर ३० हजार रुपए।

भादुड़ी : सरासर गलत। आप जिस कमरे की बात कर रहे हैं, आप उसी कमरे में बैठे हैं। यह कमरा मेरा दफ्तर ही नहीं, बोर्ड रूम भी है। संचालक-मंडल की बैठकें भी यहीं होती हैं। आप गिन लें यहां चौदह डायरेक्टरों के बैठने की व्यवस्था है और हमारे संचालक मंडल में ११ सदस्य हैं। रही बात घर की तो क्या मेरे घर पर अध्यक्ष बनने के पहले साजसज्जा नहीं थी? कार्पोरेशन का एक भी फर्नीचर मेरे घर पर नहीं है। घर पर मेरा अपना फर्नीचर पहले से था। फ्रिज भी पहले से था। शासन की इस मद में एकमुश्त पंद्रह हजार रुपए खर्च करने की अनुमति है, लेकिन मैंने घर पर कुल आठ दस हजार रुपए खर्च करे होंगे। कार्पोरेशन के खर्चे से वहां कुछ परदे लगे हैं, दो तीन कमरों में जूट की कार्पेट बिछायी गयी है और गीजर लगा है। बस।

माया : क्या यह भी गलत है कि दफ्तर की साजसज्जा का काम आपके भांजे आशीष भट्टाचार्य को दिया गया?

भादुड़ी : सौ फीसदी सच है कि आशीष को काम दिया गया, लेकिन आशीष बरसों पहले से यहां रजिस्टर्ड आर्कीटेक्ट है। वह सालों से निगम का और निगम के गठन के पूर्व से पर्यटन संचालनालय का काम करता आ रहा है। और फिर आशीष को काम मैंने नहीं, निगम के पूर्व प्रबंध संचालक श्री बागची ने दिया था।

माया : आपकी सरकारी खर्च पर गोवा यात्रा चर्चा का विषय रही है...

भादुड़ी : इसमें रंचमात्र झूठ नहीं है कि मैंने गोवा यात्रा की थी। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थीं, लेकिन अपनी पत्नी का सारा खर्च मैंने स्वयं उठाया था।

माया : जबलपुर में आपके निर्देश पर मैक्डावल प्रीमियम की बोतल खरीदने पर भी काफी बावेला मचा है...

भादुड़ी : (हंसकर) देखो, असलियत यह है कि शराब प्रेस पार्टी के लिए खरीदी गयी थी। नाम मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इसी शहर के सीनियर पत्रकार हैं। शराब खतम हो गयी थी और उन्हें शराब चाहिए थी। इस पर मैंने शराब लाने का निर्देश दिया था। इस बारे में मैंने वोराजी को भी वस्तुस्थिति बता दी थी।

माया : खबर है कि पिछले साल होली मिलन पर आपके घर पर निगम ने तीन हजार रुपए खर्च किये। क्या सच है?

भादुड़ी : यह आधा सच है। होली मिलन समारोह मेरे घर पर हर साल होता है और निगम के खर्च पर होता है। आप पुरानी बातें करें, कृष्णपाल सिंह जब पर्यटन मंत्री थे, तब उनके घर पर होली मिलन होता था। होली मिलन में उनके यहां नाच-गाना होता था और हजारों रुपए खर्च होते थे। मैं तो दो-तीन हजार रुपए ही खर्च करता हूं।

माया : एक आरोप यह भी है कि आप निगम की नर्सरी अपने घर उठा ले गये...

भादुड़ी : अच्छा किया कि आपने यह सवाल पूछ लिया। भई, नर्सरी को खतम करने का निर्णय तो बोर्ड ने लिया था। मैं उसे अपने घर क्यों ले जाऊंगा? नर्सरी तो कैपिटल प्रोजेक्ट को सौंप दी गयी।

माया : क्या यह सही है कि आपने लखनऊ से अपने पत्रकार मित्रों को म०प्र० पर्यटन निगम के खर्चे पर बुलाया और उन्हें प्रदेश की सैर करायी थी?

भादुड़ी : बुलाया था इसलिए, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों से रिश्ते थे। मैंने वहां के पत्रकार मित्रों का फायदा लिया। यू०पी० भी एम०पी० की तरह हिन्दी भाषी प्रांत है। मैं इसी तरह पत्रकारों को बाकी स्टेट से भी बुलाऊंगा।

माया : सबसे गंभीर आरोप यह है कि आपके पर्यटन निगम में आने के बाद निगम में अनियमितताएं बढ़ी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे?

भादुड़ी : सचाई यह है कि कार्पोरेशन कुछ लोगों की बपौती हो गयी थी। चोरीचकारी शुरू हो गयी थी। हम आये तो हमने चोरीचकारी, बपौती बंद की। बस लोग हमारे दुश्मन हो गये। दरअसल, पहले किसी चेयरमैन ने इस निगम पर ध्यान नहीं दिया। कृष्णपाल सिह पहले इसके चेयरमैन थे, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं थी। मैं पहला चेयरमैन हूं, जो रोज सबेरे दस बजे से शाम पांच बजे तक दफ्तर में बैठता हूं। कुछ अखबार मेरे पीछे पड़े हैं। मैं यह पूछता हूं कि यह कहां की पत्रकारिता है कि बगैर जांचे-पड़ताले आरोप-पे-आरोप छापते जाओ और आदमी को सफायी का मौका भी न दो। मैंने फिजूलखर्ची की नहीं, उलटे रोकी है। मुझे स्वागत-सत्कार पर १५ हजार रुपए सालाना खर्च करने की छूट हैं, कितु मैंने वित्त सचिव शिवरमण को पत्र लिखा कि स्वेच्छा से बीस प्रतिशत कटौती लागू करता हूं। इसी प्रकार मैंने टी०ए० बिलों पर सीलिंग लगायी कि बिल ३५ हजार रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होंगे। मेरे आने के बाद एक साल में १८ लाख रुपए का घाटा कम हुआ है। अगले साल हम मुनाफे की स्थिति में आ जायेंगे।

—**भेंटकर्ता : सुधीर सक्सेना**

भादुड़ी के घर को उनके मनमाफिक बनाने और सजाने-संवारने में निगम को अपने खाते से १५ हजार रुपए अतिरिक्त व्यय करने पड़े। इसके अलावा, श्री भादुड़ी ने निगम की नर्सरी को भी अपने आवास पर 'शिफ्ट' करवा लिया। शानो-शौकत के शौकीन श्री भादुड़ी ने पदभार संभालने के बाद एक और काम किया। उन्होंने अपने कमरे की साज-सज्जा पर ७५ हजार रुपए खर्च किये। कार्यालय की अंतर्सज्जा का काम उन्होंने किसी और को नहीं, वरन अपने भांजे आशीष भट्टाचार्य को दिया। बताते हैं इसके लिए टेंडर भी नहीं बुलाये गये।

के प्रबंध संचालक पद पर आसीन थे, लेकिन उनकी अध्यक्ष श्री भादुड़ी से पटरी नहीं बैठी और अंततोगत्वा श्री बागची को वहां से विदा होना पड़ा। उनकी जगह पर आये आई०ए०एस० अधिकारी जे०एल० अजमानी। श्री अजमानी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध संचालक पद पर आये तो कुछ ठान के आये थे। उन्होंने आते ही ऐसे ताबड़तोड़ कदम उठाये कि निगम में हायतौबा मच गयी। प्रबंध संचालक बनने के पांच महीनों के भीतर श्री अजमानी ने ७८ लोगों के तबादले किये और करीब ४० लोगों को नौकरी से निकाला। छोटे-बड़े अधिकारियों को कमरे में बुलाकर कैफियत मांगने का दौर भी शुरू हुआ। नतीजा यह हुआ कि प्रबंध संचालक के कथित तुगलकी आदेशों के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत के दरवाजे खटखटाये। श्री अजमानी के कृत्यों और फैसलों से सर्वाधिक क्षुब्ध व रुष्ट हुई एम०पी० टूरिज्म होटल एंड मोटल आफिसर्स असोसिएशन। असोसियेशन ने दिसंबर, १९८६ में श्री अजमानी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया जो करीब तीन हफ्ते चला। इसके पूर्व श्री अजमानी ने आते ही निगम-कर्मियों को कसने का खेल शुरू कर दिया था। चार्ज लेने के पांच दिन बाद ही आदेश क्र० ७७८४/२/स्था/प्रशा/प वि नि/८६ के जरिये उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधकों, संभागीय पर्यटन अधिकारियों और प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे बगैर प्रबंध-संचालक यानी उनकी अनुमति के मुख्यालय से किसी भी स्थान को भ्रमण पर न जायें। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि बिना विशेष कार्य के भ्रमण पर जाने से निगम पर अधिक व्यय भार पड़ता है।

निगम से परिचित लोगों का कहना है कि निगम में काफी समय से एक 'काकस' हावी है। इस काकस में एस०ए० हसन, एल०एम० पंत, हर्ष वर्मा और ओ०पी० कपूर के नाम लिये जाते हैं। इन लोगों को निगम में डेढ़ दशक से ज्यादा अरसा हो चुका है। १९ जुलाई, १९८१ को जब प्रवीर सेन प्रबंध संचालक थे, संचालक मंडल की बैठक में सीनियर एक्जीक्यूटिव्ज के चार पद निर्मित किये गये थे और २२ जुलाई को एक आदेश के जरिये तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पंत को वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक प्रबंधक यो और सहायक प्रबंधक चालन श्री कपूर को प्रबंधक चालन पदस्थ कर दिया गया था। आज ये लोग निगम के आला अफसर हैं। चौथे अधिकारी श्री हसन प्रबंध संचालक के खासे प्रियपात्र बताये जाते हैं। श्री अजमानी ने निगम में आगमन के कुल जमा दस दिन बाद उप महाप्रबंधक (परिवहन) का पद निर्मित किया और ठीक उसी दिन एस०ए० हसन को उस पद पर नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति से लोग इस नाते क्षुब्ध हुए, क्योंकि तकनीकी पद पर एक गैर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी।

श्री अजमानी द्वारा कुछ और नियुक्तियों के प्रसंग चर्चित हैं। जे०के० श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को होटल/मोटल प्रबंधक पद पर समेकित वेतन पर नियुक्ति दी गयी, जबकि विज्ञापन में नियमित वेतनमान पर नियुक्ति का उल्लेख था। दूसरे श्रीवास्तव के पास होटल प्रबंधन व केटरिंग योग्यता नहीं थी। इसी प्रकार, बगैर विज्ञापन के उप-महाप्रबंधक (विपणन) पद पर श्रीमती के०जेड० रिजवी नामक महिला की नियुक्ति की गयी। श्री अजमानी पर तब भी उंगलियां उठीं, जब उन्होंने विवादास्पद श्री पंत को कार्मिक के साथ-साथ परचेज सेक्शन का भी महाप्रबंधक बना दिया। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के क्रम में श्री अजमानी पर अनेक आरोप लगे हैं। जैसे, उन्होंने अकारण तबादला कर दिया, वेतन रोक लिया, डराया-धमकाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अपने पुत्र के स्टाल पर निगम के रसोइये की ड्यूटी लगायी। कुमारी कल्पना जनबंधु नामक सूचना सहायक की बदली इंदौर से उज्जैन कर दी गयी, जबकि वह घर में कमानेवाली अकेली सदस्य थी। इसी प्रकार, श्री अजमानी की अक्तूबर, १९८६ में ताशकंद यात्रा पर भी नुक्ताचीनी की गयी। सबसे अधिक मखौल उनके निगम की इकाइयों में चूहों से निपटने के लिए बिल्लियां पालने के आदेश का उड़ाया गया (हालांकि कलेक्ट्रेट में फाइलों की सुरक्षा हेतु बिल्लियां पालने का प्रावधान है और दिल्ली में कनिष्क जैसे होटल में बिल्लियां पाली गयी हैं)। भारी पैमाने पर तबादलों और लोगों को नौकरी से निकालने के अलावा श्री अजमानी ने एक और महत्वपूर्ण काम यह किया कि निगम की इकाइयों में कमरों के किराये में पचीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

सिक्के का दूसरा पहलू : आई०ए०एस० श्री अजमानी बरसों सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय

वीरेंद्र बहादुर सिंह : सफेद हाथी ?

खैरागढ़ रियासत के पूर्व महाराजा और निगम के वर्तमान उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह पर्यटन क्षेत्र के पुराने और एक तरह से स्थायी महारथी हैं। संचालक मंडल की बैठकों को छोड़ दें, तो वह कभी कार्यालय नहीं आते। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विस्तार और उत्थान में उनका योगदान आज भी दशकों बाद शोध का विषय है। स्थूलकाय श्री सिंह के निगम के खाते में दर्ज व्यय को देखते हुए उन्हें अनायास 'सफेद हाथी' की संज्ञा दी जा सकती है। गत वर्ष अध्यक्ष श्री भादुड़ी और उनके स्टाफ का यात्रा-भत्ता जहां करीब २७ हजार रुपए था, वहीं उपाध्यक्ष और उनके स्टाफ ने इस अवधि में यात्राओं पर ८० हजार रुपए से अधिक राशि खर्च की। अध्यक्ष के पास हालांकि उपाध्यक्ष से दो फोन अधिक हैं, किंतु उपाध्यक्ष का दूरभाष व्यय अध्यक्ष के व्यय से अधिक है। और-तो-और उपाध्यक्ष और उनके स्टाफ का मेडिकल व्यय इतना भारी-भरकम है कि एकबारगी विश्वास नहीं होता। 'माया' के सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार सन् ८६-८७ की अवधि में अध्यक्ष और उनके स्टाफ पर निगम का कुल १,६७,०७७ रुपए का खर्च आया, जबकि सामान्य अवधि में उपाध्यक्ष और उनके स्टाफ पर २ लाख ६८ हजार रुपए से अधिक रकम खर्च हुई। पता चला है कि इस बारे में श्री तरुण कुमार भादुड़ी ने मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का ध्यान आकृष्ट किया है, किंतु उपाध्यक्ष के पुत्र सांसद शिवेंद्र बहादुर सिंह के प्रभाव मंडल से आक्रांत श्री वोरा अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सके हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वीरेंद्र सिंह की बहू (शिवेंद्र बहादुर के बड़े भाई की पत्नी) श्रीमती रश्मि देवी खैरागढ़ से विधान-सभा की सदस्य हैं। ऐसे में सफेद हाथी पर अंकुश का इस्तेमाल होना मुश्किल लगता है।

■

में काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने में छपी खबरों से क्षुब्ध होकर १६ नवंबर, '८६ को अत्यंत गोपनीय आदेश निकाला था कि अध्यक्ष, प्रबंध संचालक और महाप्रबंधक (प्रचार) के अलावा निगम का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी संवाददाता को किसी किस्म की जानकारी न दे। बहरहाल, श्री अजमानी से 'माया' संवाददाता की लंबी चर्चा हुई और इस मुलाकात के दौरान वह यह कहने से नहीं चूके कि अखबारनवीस बगैर पुष्टि या प्रमाण के खबरें छाप देते हैं। श्री अजमानी ने वार्तालाप के दौरान यह बात जोर देकर कही कि पर्यटन निगम एक व्यावसायिक उपक्रम है, लिहाजा अब और घाटा तथा किसी भी कर्मचारी की काहिली को सहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तबादले निगम के ढांचे व काम को और अधिक सक्षम व कारगर बनाने के मकसद से किये गये हैं। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मुद्दे पर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि बगैर काम के किसी को नौकरी देने और उसे बिठाये रखने का क्या औचित्य है? श्री भट्टाचार्य को अंतर्सज्जा का काम देने के बारे में उनका कहना था कि श्री भट्टाचार्य सन् १९७८ से पंजीकृत वास्तुविद हैं और उन्हें अतीत में खजुराहो में होटल पायल व फिलहाल भोपाल में होटल पलाश में आंतरिक साज-सज्जा का काम सौंपा जा चुका है। कर्मचारियों के न्यायालय की शरण में जाने की चर्चा चली तो उन्होंने बताया कि अदालत ने सुधीर मलिक, ओ०वी० सुहाग व पी०के० सोहनी की याचिका खारिज कर दी है। प्रबंधक श्री मलिक ने मुक्की से सागर तबादले, वरिष्ठ प्रबंधक श्री सुहाग ने निलंबन और श्री सोहनी ने प्रबंधक से अकाउंटेंट पद पर रिवर्ट करने के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थीं। पांच अन्य याचिकाएं अभी लंबित हैं।

"इट वाज रियली वेरी बैडली मैनेज्ड"—निगम के खस्ताहाल को उजागर करते हुए श्री अजमानी ने कहा—"वी आर ट्राइंग टु चेक द पिल्फरेज"। इकाइयों में किराया-दरों में वृद्धि की गयी है, लेकिन इसके साथ ही सुबह का चाय-नाश्ता निःशुल्क दिया जाने लगा है। निगम में सुधार से पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में गत वित्तीय वर्ष में ३० हजार सैलानियों के मुकाबले इस वर्ष ४० हजार सैलानी आये। इसी प्रकार ८६-८७ की पहली तिमाही [illegible] निगम की आय में ८५-८६ की पहली तिमाही के मुकाबले करीब २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम ने विगत दिनों राज्य शासन को पुराने ब्याज की लगभग पौने दो लाख रु० और बरसों पुराने संपत्ति कर की राशि का भी भुगतान किया है। निगम के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन दिये गये हैं। इसके अलावा, सन् ८७-८८ की अवधि में नये स्थानों पर होटल व मोटल बनाने के १६ प्रस्ताव निगम ने भारत सरकार को भेजे हैं, जिनमें से आठ स्वीकृत हो गये हैं। इन पर छह करोड़ रु० का खर्च आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि होटल पंचानन, भोपाल, मोटल सागर और मोटल रायपुर के प्रबंधकों के विरुद्ध इस कारण कार्रवाई की गयी है, क्योंकि वे निगम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और वहां आय में कमी हुई। श्री अजमानी ने इससे इनकार किया कि वह ताशकंद सैर-सपाटे के लिए गये थे। उन्होंने कहा कि वह वहां से २५ लाख रु० का बिजनेस लाये हैं। होटल-मोटल असोसिएशन की शिकायतों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कथित होटल-मोटल अधिकारी असोसिएशन के साथ कोई अच्छा प्रबंधक नहीं है। यह इससे स्पष्ट है कि दिसंबर में असोसिएशन की हड़ताल के दौरान निगम को इकाइयों से अपेक्षाकृत अधिक आय हुई। अपनी पीठ ठोंकने के लहजे में उनका कहना था कि इस साल निगम को अपने इतिहास में पहली बार मुनाफा होगा। भारत सरकार ने सन् ७८ से ८६ के बीच निगम को केवल पांच वाहनों के लिए अनुदान दिया था, किंतु अकेले ८६-८७ में केंद्र सरकार ने छह वाहनों के लिए दस लाख रु० से अधिक अनुदान दिया है। निष्पक्ष आकलन करें तो श्री अजमानी द्वारा वर्णित उपलब्धियां यकीनन महत्वपूर्ण हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीत में गड़बड़ियों के कारण निगम निरंतर चौपट होता रहा है और अनियमितताओं और फिजूलखर्ची के कारण निगम के खाते में हानि और अपयश ही दर्ज हुआ है। फिलहाल, पर्यटन विभाग वन एवं राजस्व मंत्री बी०आर० यादव के पास है। सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार उनका परामर्श यदा-कदा प्रबंध संचालक को मिलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अपव्यय की प्रवृत्ति पर अंकुश कैसे लगाया जाये? प्रबंध संचालक श्री अजमानी अपने कड़े कदमों के कारण बार-बार कोसे जा रहे हैं। बहुत संभव है कि पर्यटन निगम जीवन के बीस साल पूरे करते-करते लाभ की स्थिति में आ ही जाये। मगर इतने भर से श्री अजमानी का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। निगम की भूमिका तब सार्थक होगी, जब घरेलू और बाहरी सैलानी अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश में आयें और निगम की सुविधाओं से संतुष्ट होकर उसे सराहते हुए लौटें। जाहिर है कि यह दुष्कर कार्य बगैर निगम के पूरे अमले के सहयोग व उत्साह के संभव नहीं हो सकेगा।

■

निगम की भूमिका तब सार्थक होगी, जब घरेलू और बाहरी सैलानी अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश में आयें और निगम की सुविधाओं से संतुष्ट होकर उसे सराहते हुए लौटें।

२० सूत्रीय कार्यक्रम
हाथकरघा वस्त्रोद्योग के लिए लाया है नया संदेश
श्रम को सराहेगा कला को संवारेगा
चन्देरी, महेश्वरी, बारासिवनी, टसर साड़ियों, प्रिन्टेड बैडशीट्स
फर्नीशिंग्स, मटेरियल, शर्टिंग्स, परदे का कपड़ा
जनता साड़ी एवं रेडीमेड वस्त्र आदि
मेहनत का ताना, कला का बाना
अवंति वस्त्रों का रूप सुहाना

अवंति हैण्डलूम्स
भोपाल: १ व २ जी०टी०बी० काम्पलेक्स, टी०टी०नगर
इन्दौर: (१) ५०७, कोठारी मार्केट के सामने, महात्मा गांधी रोड
(२) ३ हुकुमचन्द मार्ग, कांच मंदिर के सामने
उज्जैन: कमला नेहरू—फ्रीगंज शहीद पार्क के सामने
देहली: ८ कनिष्क शापिंग प्लाजा, १९ अशोक रोड
बम्बई: ३१४, लेमिंग्टन रोड
जयपुर: एम० आई० रोड
भिलाई: ३३, सिविल सेंटर, अवंति हैण्डलूम्स, ४९०००६
महेश्वर: १२, इंदिरा काम्पलेक्स, धामनोद रोड
नागपुर: सेकण्ड ब्यूटी बिल्डिंग मैन रोड सीताबाड़ी
कोचीन: फस्ट फ्लोर हैण्डलूम अंगाड़ी, एम०जी०रोड, कांग्रेस हाउस
जंक्शन दुर्ग: १५,१६, मोती काम्पलेक्स दुर्ग

विशेष आकर्षण पोलियस्टर हैण्डलूम्स सूटिंग व शर्टिंग्स
म०प्र०स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि० (म०प्र० शासन का उपक्रम)
तीसरी व छठी मंजिल, गंगोत्री भवन-टी०टी०नगर, भोपाल ४६२००३

म०प्र० में कमजोर वर्गों की तरक्की के लिए विशेष प्रयास

नये मध्यप्रदेश राज्य के १ नवम्बर १९५६ को गठन के समय हरिजन आदिवासियों की आबादी बहुत बड़ी संख्या में थी। आज मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। १९८१ की जनगणना के अनुसार राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या ११९.८७ लाख थी जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का २३ प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य में हरिजनों की आबादी ७३.५९ लाख थी जो राज्य की कुल आबादी का १४ प्रतिशत से कुछ अधिक है। इस प्रकार राज्य की आबादी के ३७ प्रतिशत में सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े और सर्वाधिक शोषित लोग शामिल हैं। इसके अलावा भी समाज के अन्य बहुत से पिछड़े वर्ग हैं। राज्य सरकार ने ३८३ जातियों और उपजातियों को पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता दी है, जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। इन वर्गों की आबादी राज्य की कुल आबादी का ४८ प्रतिशत है। इस प्रकार यह प्रकट है कि राज्य की आबादी का ८५ प्रतिशत भाग आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसे विशेष सहायता की आवश्यकता है। इस स्थिति में समाज के इन वर्गों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देनी होगी तभी प्रदेश में विकास के लिए किये गये हमारे प्रयास सार्थक होंगे।

साक्षरता

इन वर्गों के पिछड़ेपन के ऐतिहासिक कारणों और उन ब्यौरों में जाये बगैर जिनके कारण इनका शोषण हुआ है, यदि हम एक नजर नीचे दी गयी तालिका पर डाल लें, तो हमें इन वर्गों में साक्षरता की स्थिति भी मालूम हो जायेगी और उनके पिछड़ेपन के कारण भी समझ में आ जायेंगे।

क्रमांक	ब्यौरे	१९६१			१९८१		
		कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
१.	सामान्य	१७.१३	२७.०३	६.७३	२७.८७	३९.४६	१५.५३
२.	अनुसूचित जाति	७.८८	१४.२४	१.३४	१८.९७	३०.२६	६.८७
३.	अनुसूचित जनजाति	५.११	९.२४	०.९६	१६.६८	१७.७४	३.६०

इन वर्गों में विशेष रूप से उनकी महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अत्यधिक कम होने के कारण उनमें अज्ञान और अंधविश्वास फलते रहे और बेईमान और शोषक तबकों द्वारा उनका शोषण किया जाता रहा।

अतः इस समुदाय के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं—इनमें शिक्षा का प्रसार करना और उनका आर्थिक विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इनके लिए ५२ पूर्व मेट्रिक छात्रावास शुरू किये गये। १९८६-८७ के अंत तक इन छात्रावासों की संख्या बढ़कर २१०४ हो गयी है। १९६८-६९ में २१ मेट्रिकोत्तर छात्रावास खोले गये थे। यह संख्या बढ़कर अब १४२ हो गयी है। इसके अतिरिक्त १५ छात्रावास विशेष रूप से उन लोगों के बच्चों के लिए स्थापित किये गये हैं जो अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए हैं। इस समय आदिवासी और हरिजनों के बच्चों के लिए ३६२ आवासीय आश्रम स्कूल चल रहे हैं और २३ आश्रम स्कूल विशेष रूप से बहुत पिछड़ी आदिम जाति के बच्चों के लिए चलाये जा रहे हैं। १९८६-८७ में अनुसूचित जनजातियों के २.९१ लाख विद्यार्थी और अनुसूचित जातियों के ३.१७ लाख विद्यार्थियों को पूर्व-मेट्रिक छात्रवृत्तियां मिल रही थीं और १८,००० आदिवासी विद्यार्थी और २२,५०० हरिजन विद्यार्थियों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी जा रही थीं।

आदिवासी क्षेत्र की विशेष समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए और उन्हें विशेष तरीके से हल करने के लिए राज्य सरकार ने १९६४ में निर्णय लेकर आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का प्रबन्ध आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंप दिया है।

आदिवासियों के लिए नयी योजनाएं : पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद एकीकृत आदिवासी विकास की एक नयी व्यूह रचना अपनायी गयी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोजना बनायी गयी। इसी के साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों के एकीकृत विकास के लिए हरिजन विशेषांश योजना लागू की गयी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की योजना बनाने और उनकी मानीटरिंग के लिए अलग से आदिवासी क्षेत्र विकास योजना संचालनालय बनाया गया है। आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। एक तो क्षेत्र के विकास से संबंधित है और दूसरा हितग्राही-उन्मुख विकास कार्यक्रम है। हरिजन आदिवासी किसानों को खेती किसानी के विकसित तरीकों की जानकारी देने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें आवश्यक अनुदान और मार्गदर्शन दिया जाता है।

अत्याचारों से पीड़ित हरिजन-आदिवासियों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष १९७९ से यह योजना शुरू की गयी है। अब तक ४५४४ हरिजनों और २७१५ आदिवासियों पर इस योजना के तहत ५४.२४ लाख रुपये व्यय किये गये। आदिवासी पुनर्वास योजना के तहत जिन आदिवासियों को कृषि भूमि आवंटित की गयी है उन्हें छः माह के लिएं ६०० रुपये तक भत्ता दिया जाता है। वर्ष १९८६-८७ तक ८९४८ आदिवासी परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं।

इसी क्रम में, आदिवासी उपयोजना की व्यूह रचना एकीकृत आदिवासी विकास के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना से स्वीकार की गयी है। इसके अनुसार ४२ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं निर्मित की गयी हैं, जिनमें ३१ बड़ी परियोजनाएं हैं। छठीं पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान आदिवासियों के कुछ नये क्षेत्रों की और पहचान की गयी और २० एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं और बनायी गयीं। अब कुल ६२ परियोजनाएं हैं, जिनमें ३८ बड़ी, ८ मध्यम और १६ माइक्रो परियोजनाएं शामिल हैं।,

प्रदेश की योजना के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा और आदिवासी कल्याण के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदेश की योजना में से २१० करोड़ रुपए की राशि आदिवासी उपयोजना के लिए आवंटित की गयी। छठीं योजना अवधि में यह आवंटन बढ़कर ६२९ करोड़ रु० हो गया और सातवीं योजना में इस के लिए १३०० करोड़ रु० आवंटित किये गये। आर्थिक विकास की योजनाओं के अंतर्गत ७.६३ लाख आदिवासी परिवारों को छठीं योजना अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया। यह ७.७६ लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लक्ष्य का ९८.२३

"मुख्यमंत्री ने आदिवासी बालिका की पीठ ठोंकी"

ग्यारह साल की एक आदिवासी बालिका शर्मिला उयके को परीक्षा में अव्वल आने का सबसे बड़ा पुरस्कार तब मिला जब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा ने पचमढ़ी में उसके स्कूल पहुंच कर उसे बधाई दी। श्री वोरा ने शर्मिला उयके के साथ तस्वीर उतरवायी और प्रोत्साहन के बतौर उसे ५२५ रुपये दिये ।

आदिवासी कन्या आश्रम की यह छात्रा इस वर्ष मिडिल की परीक्षा में पूरे पचमढ़ी में सबसे ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण हुई है। मुख्यमंत्री की इस उदारता पर वहां उपस्थित सभी छात्राओं ने भारी करतल ध्वनि कर अपनी खुशी का इजहार किया।

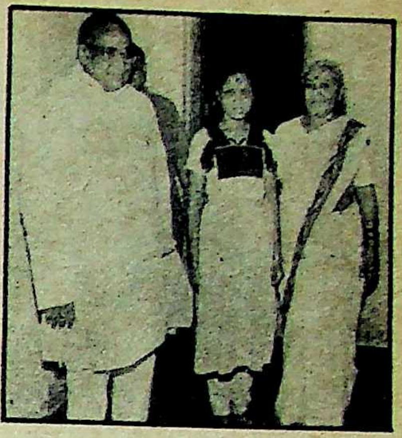

प्रतिशत था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ६.२१ लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य है।

हरिजन विशेषांश योजना : यह अनुभव किया गया कि समेकित आदिवासी विकास के लिए आदिवासी उपयोजना की तरह अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार की जाये। सन् १९७९-८०.से हरिजन विशेषांश योजना शुरू की गयी। अब सभी विकास विभागों ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अपने योजना बजट में राशि निर्धारित की है और इससे परिवार मूलक आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास विभागों द्वारा हरिजन विशेषांश योजना के तहत २०६ करोड़ रुपए व्यय किये गये और अनुसूचित जाति के ७.२३ लाख परिवारों को आर्थिक मदद दी गयी जबकि लृक्ष्य ७.४५ लाख परिवारों की मदद का था।.सातवीं योजना अवधि में हरिजन विशेषांश योजना के अंतर्गत ४१४ करोड़ रुपए आवंटित करने और १०.२७ लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है।

हरिजन विशेषांश योजना के अंतर्गत चुने हुए क्षेत्रों की प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

१. हरिजन बहुल जनसंख्या वाले विद्युतीकृत गांव	१७,११५
२. सिंगल प्वाइंट बिजली कनेक्शन	२.७८ लाख अनुसूचित जाति परिवारों को
३. १९८५-८६ के दौरान भूखण्डों का आवंटन	१८,००० अनुसूचित जातिं के परिवारों को
४. रेशम पालन कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों को रोजगार	९००० अनुसूचित जाति के परिवारों को
५. शुष्क शौचालयों का फ्लश शौचालयों में परिवर्तन	१०,००० ग्रामों में (कुल हरिजन बहुल ग्रामों का लगभग ९२ प्रतिशत)

अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक वंचित समूहों में साक्षरता प्रसार, हरिजन बस्तियों में विकास केन्द्रों की स्थापना और चर्मकारों के लिए बनायी गयी योजनाओं पर पिछले वर्षों में अमल किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाये गये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार इस तरह की ३५ संस्थाओं को सहायता अनुदान दे रही है।

केन्द्रीय सहायता

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को न केवल प्रायोजित किया है, बल्कि इनके क्रियान्वयन के लिए उदार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी है।

राज्य सरकार ने भी इन वर्गों के हितों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से अनेक कदम उठाये हैं। ऊंची ब्याज दरों पर सूदखोरों द्वारा दिये जाने वाले कर्जों को माफ किया गया और इन साहूकारों के पास गिरवी रखे गये आभूषणों और सामान को उनके सही मालिकों को वापस दिलवाये गये। धोखा देकर गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों से छीनी गयी जमीनें भी वापस दिलायी जा रही है। भूमि संबंधी विवादों के मौके पर ही निराकरण के उद्देश्य से चलित राजस्व न्यायालयों के आयोजन भी किये गये हैं जिनके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इनके माध्यम से वर्षों से लंबित नामान्तरण आदि के प्रकरण ग्राम-वासियों की चौखटों पर निपटाये गये।

हरिजनों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिक अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से इन वर्गों में नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में भी मदद मिल रही है। इन अधिकारों के उल्लंघनों की घटनाओं पर नजर रखने और इसके अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का दायित्व भी यह प्रकोष्ठ निभा रहा है।

हरिजनों के विरुद्ध अत्याचारों की शिकायतों की जांच करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी संभागों में विशेष पुलिस थानों की स्थापना की गयी है, जो हरिजन थाने कहलाते हैं। हरिजनों तथा हिन्दू समाज के अन्य वर्गों के बीच भावनात्मक एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से हरिजनों और सवर्णों के बीच वैवाहिक संबंधों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना भी प्रदेश में संचालित की जा रही है। ऐसे सवर्ण हिन्दुओं को शासन द्वारा आर्थिक सहायता, रियायतें और पुरस्कार दिये जाते हैं। इन वर्गों के उत्थान में संलग्न सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनकी सेवाओं के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। मध्यप्रदेश इन प्रथम राज्यों में से है जहां एक लाख रुपए का राष्ट्रीय इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे और श्री रामेश्वर कंवर 'गहिरा गुरु' शामिल हैं, जिन्होंने समाज के अधिक कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण में अपना सारा जीवन लगा दिया। राज्य स्तर पर ५०,००० रु० का समाज सेवा पुरस्कार भी उन प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया गया है जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

सदियों के दमन, शोषण, विपन्नता और उपेक्षा ने समाज के इन बड़े वर्गों को उन्हीं के अपने अधिक सौभाग्यशाली भाइयों से काफी पीछे छोड़ दिया है। इन्हें उनकी बराबरी पर आने में अभी बहुत रास्ता तय करना है। राज्य शासन ने उन्हें प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये हैं ताकि वे दिन शीघ्र ही आये, जब वे इस मध्यप्रदेश के बराबरी के नागरिक बने, जिसके जनजीवन को वे एक अद्भुत छटा और जीवन का सहज उल्लास देते हैं।

श्याम बेनेगल का सरकारीकरण ?

भारत के श्रेष्ठतम ११ फिल्मकारों में श्याम बेनेगल की भी गणना की जाती है। १९७३ में उन्होंने 'अंकुर' जैसी फिल्म बनाकर फिल्म निर्माण विधा की दिशा ही बदल दी थी। कला फिल्मों के निर्माण में इतालवी फिल्मों की क्रांति से अभिभूत भारत में नव-फिल्म या कला फिल्म के सेनापति जब गोदार्द, फेलिनी, वाइकोंती, इंगमार बर्गमैन की व्याख्याओं में फिल्म निर्माण की सफलता एवं लोकप्रियता का अर्थ ढूंढ़ते हुए 'उसकी रोटी' (मणि कौल), '२९ डाउन' (अवतार कौल), 'माया दर्पण' (कुमार शाहनी), 'उसकी कहानी' (बासु भट्टाचार्य) व 'बदनाम बस्ती' (प्रेम कपूर) जैसी फिल्मों का निर्माण कर सुर्खियों का विषय बन रहे थे और कला फिल्मों के आंदोलन पर दलीलें झाड़ रहे थे, श्याम बेनेगल ने १९७३ में चुपके से 'अंकुर' फिल्म बना डाली।

'अंकुर' के निर्माण के समय कला-फिल्मकार दो धाराओं में विभाजित हो गये थे। एक धारा में थे मणि कौल, कुमार शाहनी, अवतार कौल, अरुण कौल आदि, जो भारत में वाइकोंती या गोदार्द या फेलिनी या बर्गमैन की शैली में फिल्में बना कर कला फिल्मों की जमीन तलाश कर सुर्खियों का विषय बनकर कला-आंदोलन के झंडाबरदार बन गये थे। वे नाम तो कमा रहे थे, लेकिन फिल्म की नीरसता, कथ्य के ऊबाऊपन के कारण दर्शकों की भीड़ नहीं जुटा पा रहे थे। दूसरी जमात में थे मृणाल सेन (भुवन शोम), बासु चटर्जी (सारा आकाश) जिनकी फिल्में बाक्स आफिस पर सफल हुई थीं और उन्होंने उनके जरिये लोकप्रियता भी हासिल कर ली और दर्शकों की भीड़ भी जुटा ली थी। बासु चटर्जी की 'सारा आकाश' और 'रजनीगंधा' की सफलता से प्रभावित होकर बासु भट्टाचार्य ने मणि कौल का गोदार्दी पथ छोड़कर कलात्मक फिल्मों का रास्ता पकड़ लिया और 'अनुभव' जैसी सफल फिल्म बना डाली। यह महज इत्तिफाक था कि बासु भट्टाचार्य ने जिस बासु चटर्जी की सफलता से प्रेरणा ली वही 'तीसरी कसम' के निर्माण के समय उनके सहायक थे।

श्याम बेनेगल की 'अंकुर' की बाक्स आफिस सफलता ने कला फिल्मों के आंदोलनकारियों एवं कलात्मक फिल्में बनानेवालों को यह अहसास कराया कि कोरी सैद्धांतिक या लीक से हटकर हलकी-फुलकी फिल्मों द्वारा फिल्म निर्माण-विधा में बदलाव नहीं लाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए जरूरी है—आम आदमी की जिंदगी के यथार्थ एवं अनछुए पक्षों को पूरी संवेदना एवं प्रभावशाली ढंग से पेश किया जाये। श्याम बेनेगल ने 'अंकुर' के बाद 'निशांत' बनाकर इस तथ्य पर एक और मुहर लगा

दी। इन फिल्मों ने उन्हें यथार्थपरक फिल्में बनानेवालों की श्रेणी में सबसे आगे ला बिठाया तो 'भूमिका' ने संवेदनशील फिल्मकारों (ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार आदि) की श्रेणी में ('भूमिका' मराठी फिल्मों की प्रख्यात अभिनेत्री हंसा वाडेकर की बेबाक आत्मकथा पर आधारित थी)। लेकिन श्याम बेनेगल सारे फिल्मकारों से अलग अपनी पहचान बनाने में समर्थ सिद्ध हुए।

इसके बाद उन्होंने एक तरफ गुजरात में दुग्ध सहकारी क्रांति को लेकर 'मंथन' बनायी, तो दूसरी तरफ कोठेवालियों एवं वेश्याओं की जिंदगी को मर्मस्पर्शी ढंग से छूती हुई 'मंडी' बनायी। 'मंथन' दुग्ध व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध सहकारिता आंदोलन और उससे जुड़ने तथा अंदरूनी ढंग से पनपती राजनीति और परोक्ष रूप से ऊपरवालों की दखलंदाजी की फिल्म थी। फिल्म का अंत सहकारी समिति के प्रबंधक (गिरीश कर्नाड) के ऊपरी दखलंदाजी के तहत स्थानांतरण आदेश के साथ होता है जो आज की दूषित राजनीति और भ्रष्टाचार की नियति बन गयी है।

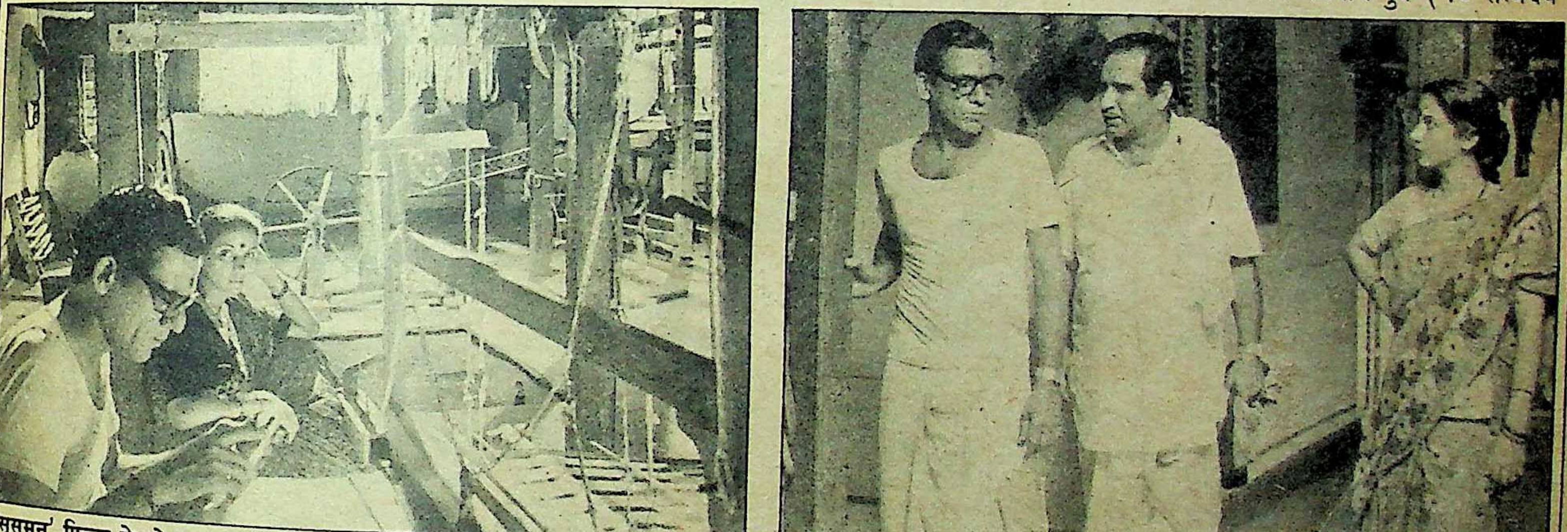
'सुसमन' फिल्म के दो दृश्य। एक में—ओमपुरी और शबाना आजमी तथा दूसरे में ओमपुरी, कुलभूषण खरबंदा और शबाना

श्याम बेनेगल की नयी फिल्म 'सुसमन', 'मंथन' की ही परंपरा की फिल्म है, जिसमें वस्त्र व्यापारियों द्वारा हथकरघा कारीगरों के शोषण के साथ-साथ उनकी संघर्षशील जिंदगी को बड़े प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है।

श्याम बेनेगल जब जिंदगी की सचाइयों को सेल्युलाइड पर उतारने के लिए सन्नद्ध होते हैं, तो दूसरे फिल्मकारों की तरह राजनीतिक एवं सामाजिक स्खलन तथा भ्रष्टाचार से कतराने की कोशिश नहीं करते, साथ ही उनके विरुद्ध विद्रोह का प्रतीकात्मक स्वर भी डाल देते हैं। 'अंकुर' के अंतिम दृश्य में एक छोटे बच्चे द्वारा अत्याचारी जमींदार की खिड़की पर फेंका जानेवाला पत्थर, 'निशांत' में जमींदार के अनाचार, बेईमानी के विरुद्ध आम आदमी के खुले विद्रोह जन-आक्रोश का रूप ले लेता है जिसकी हिंसा का शिकार समूचा जमींदार परिवार हो जाता है। इसके साथ ही श्याम बेनेगल प्रशासनिक लालफीताशाही एवं अवमूल्यन को भी दर्शाने से नहीं चूकते। जब जमींदार द्वारा अपहृत अपनी पत्नी (शबाना आजमी) को उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए स्कूल अध्यापक शहर जाकर पुलिस, प्रशासन एवं नेताओं के चक्कर लगा कर निराश गांव लौटता है और गांव की सरहद पर, जिसके एक तरफ अक्षम प्रशासन का शासन है, तो दूसरी तरफ शोषण के प्रतीक जमींदार का निरंकुश तंत्र, आकर पागलों की तरह अपने 'निर्जीव' छाते पर अपना रोष उतारता है।

'भूमिका' भी शोषण की फिल्म थी, लेकिन शोषण और भ्रष्टाचार का स्वर 'अंकुर' तथा 'निशांत' से अलग था। एक-एक दाने के लिए मोहताज गरीब लड़की (स्मिता पाटील) जब फिल्मों की चमक-दमक भरी दुनिया में आती है, तो उसे सबसे पहले अपनी अस्मिता की कुर्बानी देनी पड़ती है—कभी विवशतावश तो कभी वर्तमान से पलायन की मानसिकता में। फिर यही उसकी नियति बन जाती है और 'सब कुछ' को जिंदगी का एक हिस्सा मानकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकती रहती है और उसका 'क्लीव' पति (अमोल पालेकर कभी नाराज होकर तो कभी खुश होकर यह सब देखता रहता है। 'निशांत' में भी जमींदार भाइयों के शोषण की शिकार तथा अपहृत अध्यापक-पत्नी (शबाना आजमी) भी वर्तमान को नियति मान लेती है और पति को 'क्लीव' समझ कर, उससे मंदिर में मिलकर भी उसी चिरपरिचित काल-कोठरी में स्वत: वापस लौट आती है। पति के साथ जाने की भावना उसमें होती ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है उसके पति ने जान-बूझकर जब उसे भेड़ियों के बीच पड़ा रहने दिया, तो वह क्यों 'ऐसे पुरुष' के पास वापस जाये।

'भूमिका' के बाद 'मंथन', 'मंडी', 'त्रिकाल एवं 'सुसमन' में श्याम बेनेगल के तेवर बदल जाते हैं और एक परिपक्व फिल्मकार का रूप उजागर हो उठता है जो जिंदगी की अन्य दूसरी सचाइयों को उजागर करने के लिए बेचैन दिखलायी पड़ता है। इसीलिए बाद की फिल्मों के कथ्य बदल जाते हैं। कहीं रोमांटिसिज्म (त्रिकाल) दिखलायी पड़ता है, तो कहीं पारिवारिक समस्याएं (सुसमन) और कहीं जिंदगी को सहजता से जीने की कशमकश (मंडी) दिखलायी पड़ती है।

'मंथन' के बाद श्याम बेनेगल ने शशि कपूर के लिए 'जुनून' एवं 'कलयुग' बनायी। ये दोनों फिल्में न केवल स्टार कास्ट थीं, बल्कि इनकी निर्माण लागत इतनी अधिक थी कि जितने में श्याम बेनेगल बड़ी आसानी से अपनी शैली में तीन-चार फिल्मों का निर्माण उन्हीं सितारों को लेकर कर सकते थे। 'जुनून' के निर्माण पर लगभग ७० लाख रुपए व्यय हुए थे। 'जुनून' भारतीय आजादी के प्रथम चरण, जिसे 'सिपाही-विद्रोह' का नाम दिया गया था, की फिल्म थी।

'जुनून' के बाद बनी 'कलयुग' श्याम बेनेगल की फिल्म मेकिंग में आनेवाले बदलाव का संकेत चिन्ह थी, जिससे लगता था कि वह अपने कथ्य के कैनवास को और भी विस्तृत बनाते जा रहे हैं। यों इसका संकेत तो 'जुनून' में ही मिल गया था।

"महाभारत के चरित्र मुझे शुरू से ही 'हांट' करते रहे थे— 'अंकुर' के निर्माण के पहले से ही।" श्याम बेनेगल का कहना था, "मैं अकसर महाभारत के चरित्रों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखता और उनके बारे में सोचता। अकसर दुबे (पं० सत्यदेव दुबे, जिन्होंने श्याम बेनेगल की अधिकांश फिल्मों की पटकथाएं एवं संवाद लिखे), शमा जैदी, (कास्ट्यूम डिजाइनर), गिरीश (गिरीश कर्नाड) आदि से इस बारे में बातें होती रहती थीं। 'जुनून' के निर्माण के ही दौरान शशि कपूर से भी इस बात पर चर्चा हुई तो वह तुरंत 'जुनून' के बाद इसी विषय पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गये।" और इस तरह 'कलयुग' (यंत्र-युग) का निर्माण हुआ जिसमें महाभारत के बहुचर्चित पात्रों—कौरवों, पांडवों को एक औद्योगिक घराने के रूप में पेश किया गया था। नियति का यह भी एक चक्र था कि 'कलयुग' के प्रदर्शन के बाद वर्तमान कई बड़े औद्योगिक घरानों की अंदरूनी जिंदगी भी प्रकाश में आयी जिनके पात्र 'कलयुग' के पात्रों से काफी मेल खाते थे।

श्याम बेनेगल की फिल्मों की एक विशेषता और थी। उनके खलनायक कामर्शियल फिल्मों के 'एक्सपोज्ड विलेन' जैसे नहीं होते थे, इसीलिए वह फिल्म के बुरे चरित्रों को अपनी शख्सियत को स्वत:

साक्षात्कार/श्याम बेनेगल

मैं सरकार के लिए फिल्में नहीं बनाता हूं

माया: आजकल आप सरकार और सरकारी विभागों के लिए ही फिल्में बना रहे हैं—इसकी वजह?

बेनेगल: आपका इशारा दूरदर्शन श्रृंखला 'यात्रा' और फिल्म 'नेहरू' की ओर है। है ना? कौन कहता है मैंने 'यात्रा' रेलवे विभाग के लिए और 'नेहरू' फिल्म सरकार के लिए बनायी है। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। मुझे क्या पड़ी है रेलवे विभाग और सरकार के लिए पी०आर०ओ० का कार्य करने की या दलाली करने की।

माया: आप सरकार के लिए फिल्म बनाने के बावजूद यह कह रहे हैं कि मैं सरकार के लिए फिल्म नहीं बनाता हूं—इसके मायने?

बेनेगल: मैं हर फिल्म आम लोगों के लिए बनाता हूं। मैंने 'यात्रा' बनाने का जिम्मा अपने देश की आम जनता को देखते हुए लिया। रोजाना एक करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं। डेढ़ करोड़ लोग इससे रोजी-रोटी कमाते हैं—इस प्रकार से रेल हमारी पूरी जनसंख्या को अपने आप में समेटे हुए है। पूरी 'यात्रा' के दौरान मैंने कहीं भी नहीं दिखाया है कि रेलवे और रेलवे-व्यवस्था बहुत अच्छी है—वह जैसी है वैसे ही दिखायी है मैंने। आप ही कहिए—ताज पर मेकअप लगाकर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।

माया: 'नेहरू' फिल्म भी आपने सरकार के कहने पर बनायी है?

बेनेगल: हां... लेकिन सरकार के लिए नहीं बनायी है। जो लोग ये कहते हैं कि 'नेहरू' मैंने सरकार के लिए बनायी है वे ये क्यों नहीं कहते कि रिचर्ड एटनबरो ने 'गांधी' सरकार के लिए बनायी है।

माया: फिर भी 'नेहरू' फिल्म बनाने का जिम्मा लेने का कोई तो कारण होगा।

बेनेगल: नेहरू फिल्म बनाना एक चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि इसमें गहन अनुसंधान, मेहनत और समय तो लगना ही था इसके साथ-साथ मुझे यह भी विश्वास था कि मेरी यह फिल्म पूर्ण होने पर डाक्युमेंट्री न रहकर एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जायेगी और मेरा विश्वास गलत साबित नहीं हुआ।

माया: इस फिल्म को बनाने में कितना समय लगा?

बेनेगल: नेहरू तीन घंटे की डाक्युमेंट्री फिल्म है। इसे बनाने में १९८१ से १९८४ तक का समय लगा। अनुसंधान कार्य १९८१ में शुरू हुआ, १९८३ में स्क्रिप्ट पूरी हुई तथा सितंबर १९८४ में फिल्म पूरी हुई।

माया: अनुसंधान कार्य में कौन-कौन थे आपके साथ?

बेनेगल: ये फिल्म भारत और सोवियत रूस के सहयोग से बनी है। अनुसंधान कार्य में भारत की ओर से डा० गोपाल, बी०आर० नंदा, रवींद्र कुमार और मैं तथा सोवियत के इतिहासकार श्री गोरेथ तथा रशियन भाषा में नेहरू का जीवन-चरित्र लिखनेवाले श्री जिमयालिन थे।

माया: रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 'गांधी' से आपकी फिल्म 'नेहरू' किस तरह अलग है जबकि दोनों फिल्में एक ही समय के इतिहास पुरुषों को लेकर बनायी गयी हैं।

बेनेगल: देखिए फिल्म 'गांधी' से मेरी फिल्म 'नेहरू' की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई फिक्शन फिल्म नहीं बनायी है और न ही बाहरी कलाकारों को लिया है। फिल्म 'गांधी' में बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभायी है। 'नेहरू' फिल्म के हीरो स्वयं नेहरू हैं—जो स्वयं अपनी भूमिका को निभाते हैं—अपनी कहानी स्वयं कहते हैं—यह फिल्म फर्स्ट पर्सन बायोग्राफी है जिसमें १०० वर्ष की ऐतिहासिक विश्वसनीय सामग्री है। गांधी फिल्म में नाटकीयता है, ढेर सारे मंजे हुए कलाकार हैं।

माया: अगर आपको भी नेहरू पर फिक्शन फिल्म बनाने को कहा जाता तो?

बेनेगल: जाहिर है अच्छी बनाता, फिक्शन फिल्में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

माया: नेहरू फिल्म को न तो उतनी लोकप्रियता मिली और न ही यह फिल्म चर्चित हुई, इसके कारण।

बेनेगल: इस फिल्म को भारत में लोकप्रियता नहीं मिली और न ही यह चर्चित हुई आप ऐसा कह सकते हैं, किंतु सोवियत संघ में टेलीविजन पर तो दिखाया जा चुका है साथ ही थियेटरों मे भी दिखाया गया है और इस फिल्म को सर्वोच्च सोवियत फिल्म पुरस्कार भी मिला है।

माया: इस संदर्भ में आपका यह कहना कहां तक तर्कसंगत है कि मैं फिल्म आम दर्शक के लिए बनाता हूं—जबकि नेहरू फिल्म दर्शकों तक पहुंची ही नहीं।

बेनेगल: फिल्म प्रभाग द्वारा इस फिल्म का प्रचार नहीं किया गया और न ही इस फिल्म को (एक बार टेलीविजन पर दिखाने के सिवाय) बड़े पैमाने पर दिखाया गया। फिल्म को दिखाया जाना, उसका प्रचार करना मेरा काम नहीं था—मेरा काम था एक उम्दा फिल्म बनाना जो मैंने किया।

माया: इस फिल्म के दर्शकों तक न पहुंचने पर आपको कैसा लगता है?

बेनेगल: जाहिर है दुःख तो होता ही है, कुछ कचोटता रहता है। मैंने इतनी मेहनत से फिल्म डिब्बे में बंद पड़ी रहने के लिए तो नहीं बनायी थी।

माया: इसके बावजूद आप 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' बनाने में लगे हैं।

बेनेगल: हां ऐसा होने के बावजूद मैं 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' बना रहा हूं। सरकार के कहने पर नहीं, बल्कि मुझे स्वयं लगता है कि फिलहाल जरूरत इस बात की है कि हम सभी अपने देश की ओर देखें, उसकी परंपरा और संस्कृति की ओर देखें—लोगों को दिखायें।

माया: 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में क्या खास बात होगी?

बेनेगल: इस फिल्म के रूप में मैं लोगों को मोहनजोदड़ो से लेकर अब तक की संस्कृति और परंपरा को इतने वास्तविक रूप में संजोने की कोशिश करूंगा कि वह एक विश्वसनीय दस्तावेज बन जाये। कोई व्यक्ति जानना चाहे कि आज से २५-३० सौ साल या उससे पहले भी लोगों का रहन-सहन, वेश भूषा कैसी होती थी तो 'डिस्कवरी आफ इंडिया' उसका उत्तर देगी। किसी भी राजनीतिक प्रचार से मेरा कोई लेना-देना नहीं है और न होगा—मैं एक साफ सुथरी फिल्म बनाऊंगा। दर्शकों को यह फिल्म १९८८ के मध्य से दूरदर्शन पर श्रृंखला के रूप में देखने को मिलेगी। जिसके ५२ भाग होंगे। प्रत्येक भाग ४५ मिनट का होगा।

माया: 'मंथन' फिल्म आपने दूध आंदोलन को लेकर गुजरात डेरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन के लिए बनायी थी और 'सुसमन' जो रिलीज होने वाली है वह बुनकरों के जीवन को लेकर बनायी है—इसका कारण।

बेनेगल: बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। एक कलाकार होने के नाते मैं बुनकर, शिल्पी, लेखक, चित्रकार सभी को कलाकार मानता हूं और वे वास्तव में अपने फन में माहिर होते हैं। हथकरघा तथा बुनाई उद्योग हमारे पारंपरिक उद्योग हैं, जो हमारी संस्कृति को भी समेटे हुए हैं। इचक कोंबली के बुनकरों के माध्यम से मैंने आम बुनकरों की समस्या, भावना तथा अहसास को दर्शाया है तथा उनकी ओर लोगों का ध्यान दिलाया है, क्योंकि यह लोग उपेक्षित होते जा रहे हैं।

—रमेश प्रियंकर व विद्या जैन

उभारने के लिए काफी समय देते। उनकी निजी जिंदगी को वे हूबहू उतार देते। इसीलिए वे शोषक होते हुए भी ओवर एक्सपोज्ड-अतिरंजित शोषक—नहीं लगते। उनका कर्तव्य उनकी शख्सियत को उजागर कर जाता। 'अंकुर' एवं 'निशांत' के जमींदार, 'भूमिका' का पति, 'मंथन' का थोक दुग्ध व्यापारी, 'सुसमन' के कपड़ा व्यापारी इसी तरह के चरित्र थे। उनकी अपनी मजबूरियां थीं, तो कमजोरियां भी। और श्याम बेनेगल यहीं अपनी पकड़ तेज कर देते थे।

संभवत: भारतीय फिल्म उद्योग में श्याम बेनेगल अकेले फिल्मकार हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सर्वाधिक एवं सक्षम कलाकार प्रदान किये। शबाना आजमी, अनंत नाग, सविता बजाज (अंकुर), स्मिता पाटील, गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, मोहन अगाशे, कुलभूषण खरबंदा (निशांत), नीना गुप्ता, अनिता कंवर (मंडी), पंकज कपूर, पल्लवी जोशी, अन्नू कपूर (सुसमन) आदि अनेक कलाकारों के अलावा छायाकार गोविंद निहलानी, संगीतकार वनराज भाटिया, पटकथा-संवाद लेखक पं० सत्यदेव दुबे तथा बहुत से तकनीशियन श्याम बेनेगल की ही देन हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की।

हैदराबाद में जन्मे श्याम बेनेगल पांचवें दशक में बंबई आये और यहां पर विज्ञापन तथा डाक्युमेंट्री फिल्मों का निर्माण शुरू किया। श्याम बेनेगल ने अब तक ७०० से अधिक विज्ञापन फिल्में तथा १५ से अधिक डाक्युमेंट्री फिल्में बनायी हैं। विज्ञापन फिल्मों के निर्माण के सिलसिले में ही वह ब्लेज फिल्म तथा विज्ञापन फिल्म निर्माता श्री धानेकर के संपर्क में आये, और फिल्म 'मंथन' का निर्माण किया।

१९७२ में ब्लेज इंटरप्राइजेज के मालिक श्री मोहन बिजलानी, जिनके लिए वह विज्ञापन फिल्में बनाया करते थे, ने उनके सामने एक फीचर फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा, तो श्याम बेनेगल ने इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि फिल्म-निर्माण के आर्थिक पक्ष संभालने के अलावा फिल्म में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। बिजलानी ने उनकी शर्त मान ली तो उन्होंने १९७३ में 'अंकुर' का निर्माण किया। फिर 'निशांत', 'भूमिका', 'मंडी' भी उन्हीं के लिए बनायी।

श्याम बेनेगल शुरू से ही लीक से अलग हटकर फिल्म बनाने के पक्ष में थे। १९६०-६१ में जब (स्व०) गुरुदत्त ने उनसे अपनी यूनिट में बतौर सहायक निर्देशक ज्वाइन कर लेने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। "दरअसल मैं गुरुदत्तजी का प्रशंसक था" श्याम बेनेगल 'माया' को बतलाते हैं, "लेकिन मुझे डर था कि उनके साथ काम कर मैं भी मुख्य धारावाली फिल्मों (व्यावसायिक फिल्मों को वह मुख्यधारा—मेनस्ट्रीम फिल्म कहते हैं) की परंपरा से जुड़ जाऊंगा। मैं इस तरह की फिल्मों का कट्टर आलोचक था। अगर आप किसी प्रभावशाली निर्देशक या ग्रुप के साथ काम करें तो कहीं-न-कहीं उनके विचारों का प्रभाव आप पर पूरी तरह से पड़ता है। ऐसे में आपकी अपनी सोच से भटक जाने का डर भी बना रहता है। यही डर उस समय मुझे भी लगा था और मैंने गुरुदत्तजी के ऑफर को ठुकरा दिया था।"

फिल्म 'त्रिकाल' में सोनी राजदान

'यात्रा' टी०वी० सीरियल में जरीना

फिल्मों, विशेषकर कला फिल्मों को नये तेवर और नये दर्शक देनेवाले श्याम बेनेगल ने जब पश्चिम बंगाल सरकार के आग्रह पर उसके लिए बंगला में 'आरोहण', दूरदर्शन के लिए 'नेहरू' तथा रेलवे मंत्रालय के लिए 'यात्रा', टी०वी० सीरियल के अलावा 'सुसमन' बनायी तथा दूरदर्शन के लिए 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' सीरियल बनाने की घोषणा की, तो फिल्मक्षेत्र में अचानक श्याम बेनेगल के बारे में प्रचलित सारी मान्यताएं बदल गयीं और उन्हें 'सरकारी फिल्मकार' का खिताब दे दिया गया। उन्होंने 'मंथन' आनंद (गुजरात) की सहकारी दुग्ध संस्था के लिए बनायी थी ताकि उनसे प्रेरित होकर देश में अन्यत्र भी दुग्ध सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हो सके।

'मंथन' की राजकोट के एक गांव में आउट डोर शूटिंग के दौरान जब मैंने श्याम बेनेगल से पूछा था कि 'इस फिल्म के निर्माण के बाद आपकी इमेज बदल जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि आम लोग इसे फीचर फिल्म के बजाय प्रचार-फिल्म मानेंगे' तो उन्होंने इस संभावित खतरे की ताईद की थी, इसीलिए उन्होंने बाद में 'मंथन' जैसी फिल्मों के निर्माण के अन्य आफरों को ठुकराकर, अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए 'जुनून', 'कलयुग', 'मंडी' और 'त्रिकाल' जैसी फिल्मों का निर्माण शुरू किया ('कथा सागर' टी०वी० सीरियल भी प्रस्तुत किया)।

'सुसमन' में पल्लवी जोशी

इसी दौरान उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और फिल्म से संबंधित कई राष्ट्रीय (सरकारी) संगठनों से जुड़ने का भरपूर मौका भी मिला। अपने जिस सोच एवं सिद्धांत के रास्ते से हटने की आशंका से उन्होंने गुरुदत्त जैसे प्रख्यात निर्माता-निर्देशक के साथ काम करने से मना कर दिया था, वही खतरा २५ वर्ष बाद उनके सामने आ खड़ा हुआ जब वह सरकारी तंत्रों के संपर्क में आये। आज फिल्म निर्माण में व्यस्त न होने के बावजूद उनका अधिकांश समय सरकारी मीटिंग में भाग लेने के लिए बंबई से दिल्ली तथा दूसरे प्रदेशों की राजधानियों की यात्रा, फिल्मोत्सवों में शामिल होने के लिए विदेश-यात्राओं में निकल जाता है। फलत: फिल्म निर्माण की रचनात्मक धारा से एक तरह से वह एकदम से कट गये हैं। इसका खमियाजा भी उन्हें कम नहीं भुगतना पड़ा। जिस श्याम बेनेगल की फिल्में खरीदने के लिए वितरकों में उत्साह बना रहता था, उन्हीं की दो वर्षों से तैयार 'त्रिकाल' एवं 'सुसमन' के लिए कोई वितरक नहीं मिल पा रहा है। टेलीविजन को बेचने पर निर्माण लागत न निकल पाने की आशंका से उन्हें दूरदर्शन को प्रदर्शन के लिए नहीं दे पा रहे हैं।

यह एक गुणी एवं सक्रिय रचनाकार का पराभव है या उसके 'बड़ा' एवं सरकारी तौर पर 'प्रभावशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति' बनकर रचनात्मक आंदोलन से धीरे-धीरे कट जाने की स्थिति—इसका सही जवाब तो खुद श्याम बेनेगल तभी दे सकेंगे जब वह एकांत में समूचे परिप्रेक्ष्य पर चिंतन करने और निर्णय लेने का समय, सरकारी मीटिंगों से निकाल सकेंगे।

—रवींद्र श्रीवास्तव

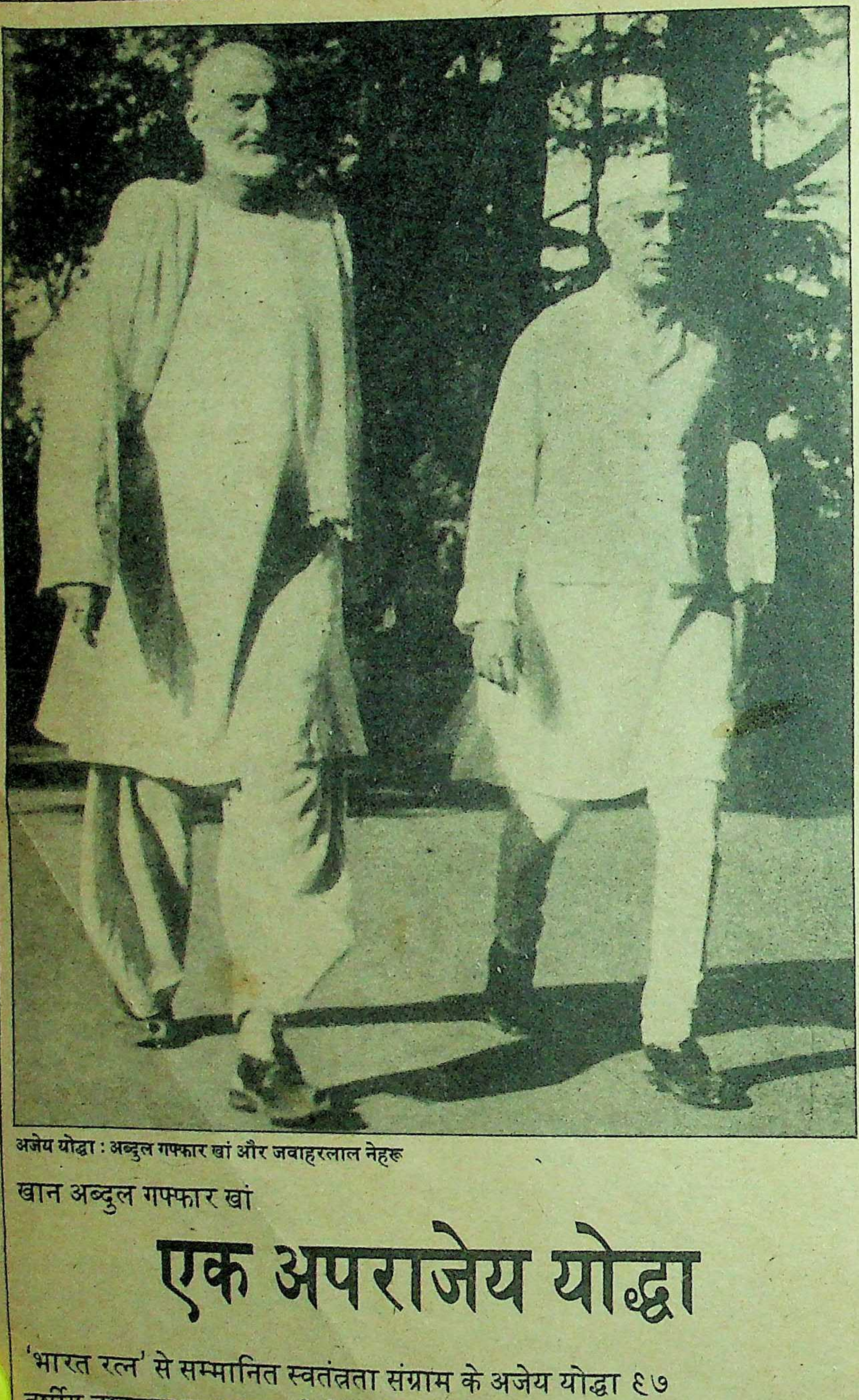

अजेय योद्धा : अब्दुल गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू

खान अब्दुल गफ्फार खां

एक अपराजेय योद्धा

'भारत रत्न' से सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम के अजेय योद्धा ९७ वर्षीय बादशाह खान आजादी से पहले और बाद में दमन के खिलाफ निरंतर संघर्षरत रहे हैं। दमनकारी ताकतों के लिए जितनी अपराजेय उनकी स्वातंत्र्य चेतना रही है, मौत के लिए उतनी ही दुर्जेय उनकी जिजीविषा सिद्ध हुई है। आजादी के लिए सतत संघर्ष के अद्वितीय प्रतीक सीमांत गांधी के जीवन का सिंहावलोकन :

सन् १९१८ के शुरुआती दिन। मरदान जेल का जेलर बहुत परेशान था। नये लाये गये कैदी को पुलिस कप्तान ने बेड़ियां पहनाने का हुक्म दिया था। पुलिस के सिपाही और जमादार उसे बेड़ियां पहनाने की हरसंभव कोशिशें कर, थक-हारकर बैठ चुके थे। सदर पुलिस थाने तथा जेल में रखी सभी बेड़ियां आजमायी जा चुकी थीं, लेकिन उस लंबी-चौड़ी कायावाले व्यक्ति के विशाल हाथ-पांवों में बेड़ियां अंट ही नहीं पाती थीं। अंततः क्रूर जेलर जेल में उपलब्ध सबसे बड़ी साइज वाली बेड़ियां, उस युवक को पहनाकर ही हटा, लेकिन इस प्रयास में उस नये कैदी के हाथ-पैर लहूलुहान हो गये। जेलर यह देखकर अचंभित था कि रौलेट ऐक्ट का विरोध करने की हिम्मत करनेवाले उस युवक ने बेड़ियों से लहूलुहान हो जाने पर भी उफ नहीं किया था—मुस्कराता भर रहा था।

उस युवक का नाम था—खान अब्दुल गफ्फार खां। १९१८ में प्रथम विश्वयुद्ध खतम हो जाने पर १९१९ में जब रौलेट ऐक्ट लागू किया गया तो समूचे देश में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई थी। फलतः सीमांत तथा दूसरे कई संवेदनशील इलाकों में मार्शल ला लागू कर दिया गया, लेकिन अब्दुल गफ्फार खां ने इसकी परवाह न कर देश के दूसरे हजारों-लाखों युवकों की तरह रौलेट ऐक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों में भाग लिया और गिरफ्तार हुए।

१७ दिसंबर, १९२१ को जब उन्हें गिरफ्तार कर तीन वर्ष की सजा भुगतने के लिए पेशेवर जेल की कसूरी चक्की में बंद किया गया और दो महीने बाद डेरा इस्माइल खां जेल में भेजा गया तो उन्हें रोग के कीटाणु लग गये और वह बीमार हो गये। इसके बाद उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया जहां उनकी भेंट, उसी जेल में बंद लाला लाजपत राय, मलिक लाल खां आदि नेताओं से हुई। इन नेताओं का असर उन पर न पड़ने पाये, इसलिए उन्हें डेरा गाजी खां जेल भेज दिया गया।

एक नयी लौ का प्रकाश : सन् १९२६ में वह हज-यात्रा के लिए गये। इस बीच कई ऐसे हादसे हुए जिसने उनके मन को हिलाकर रख दिया। हज-यात्रा ने उनकी सोच को एक नयी दिशा दी। उन्होंने सोचा कि जब तक लोगों में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण की लौ नहीं जलायी जाती तब तक उन्हें ब्रितानी हुकूमत की दासता और वर्तमान त्रासदायक स्थितियों से मुक्त नहीं कराया जा सकता। उस समय अफगानिस्तान, नार्थ वेस्ट फ्रंटियर तथा आदिवासी क्षेत्रों में रहनेवाले पठानों की संख्या लगभग एक करोड़ थी और उनमें से ९८ प्रतिशत अशिक्षित एवं गंवार थे, जो बात-बात पर लड़ने-मरने के लिए तैयार हो जाते थे। उन्होंने अंजुमन इस्लाहउल अफगाना संस्था की स्थापना की और सामाजिक जागरण के लिए पद-यात्रा तथा राजनीतिक जागरण व शिक्षा-प्रसार के लिए 'पख्तून' पत्र का प्रकाशन शुरू किया। गफ्फार खां खिलाफत कमेटी से जुड़े हुए थे।

१९२० के अखिल भारतीय खिलाफत अधिवेशन (दिल्ली) में भाग भी लिया था, लेकिन २८ दिसंबर, १९२८ को कलकत्ता में हुए खिलाफत सम्मेलन की एक घटना ने उन्हें धीरे-धीरे खिलाफत कमेटी से दूर तथा कांग्रेस के निकट ला दिया। खिलाफत सम्मेलन के दौरान एक पंजाबी मुस्लिम नेता ने जब मौलाना मुहम्मद अली की कड़ी आलोचना की तो वह गालियों पर उतर आये, इस पर वह नेता छुरा लेकर मुहम्मद अली पर लपका, लेकिन गफ्फार खां ने लपक कर उसे पकड़ लिया और मोहम्मद अली को भी अभद्रता और हिंदु-सभ्यता-संस्कृति की निंदा करने के लिए मना किया तो मुहम्मद अली उलटे उन पर बरस पड़े—'अच्छा तो अब जंगली-निरक्षर पठानों को भी हमें सीख देने की तमीज आ गयी है।' मुहम्मद अली के भड़काने पर उनके नरमदिल भाई शौकत अली कई वर्षों तक गफ्फार खां के जानी दुश्मन बने रहे। और अंततः एक दिन उन्होंने भूल सुधारते हुए कहा था, "शौकत को खुदा भी माफ नहीं करेगा, एक संत के विरुद्ध मुझे भड़का कर उसका दुश्मन बनाने के लिए।"

गफ्फार खां कांग्रेस अधिवेशनों में भी कभी-कभार जाया करते थे। उसी समय कलकत्ता में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में भी वह गये और वहां की अनुशासनबद्धता एवं महात्मा गांधी तथा नेहरू के काम करने के ढंग से काफी प्रभावित भी हुए। १९२९ के कांग्रेस अधिवेशन (लखनऊ) में भाग लेने के लिए वह विशेष रूप से लखनऊ गये। इस अधिवेशन में वह गांधीजी व पं० नेहरू से मिले और उनसे पठानों की मूल समस्याओं के बारे में काफी लंबी बातचीत भी की।

'खुदाई खिदमतगार' बनाम लाल कुर्तीवाला: उतमान जई वापस लौटने पर उन्होंने सितंबर १९२९ में 'खुदाई खिदमतगार' की स्थापना की और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर शपथ ली कि उन पर कितना ही अत्याचार-अनाचार क्यों न हो, वे हथियार नहीं उठायेंगे और न ही प्रतिशोध की भावना रखेंगे। हर अत्याचार का विरोध अहिंसा और सत्याग्रह से करेंगे। बहादुर पठानों के लिए यह नायाब अनुभव था। कुछ ही दिनों के भीतर 'खुदाई खिदमतगार' के सदस्य लाल कुर्तीवाले के नाम से प्रसिद्ध हो गये। इसका भी एक दिलचस्प वाकया है।

'खुदाई खिदमतगार' मेहनतकश लोग थे। सभाओं में जमीन पर बैठने, भाग-दौड़ आदि में कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। ऐसे में कुछ ने अपने कपड़े (कमीज-सलवार, जाकेट, पगड़ी) गाढ़े रंग में रंगने के लिए एक रंगरेज को दिये जिसने उन्हें देवदार की छाल से बने गहरे घोल में, जिसे चमड़ा सिझाने के लिए तैयार किया गया था, में डाल दिया। कत्थई-लाल रंगवाले अपने इन कपड़ों को पहनकर कुछ खिदमतगार जब दूसरी बैठक में शामिल हुए तो गफ्फार खां तथा दूसरे साथियों को भी यह रंग भा गया फलतः सभी ने अपने कपड़े उसी रंगरेज के यहां से उसी रंग में रंगवा लिए। धीरे-धीरे लोगों ने उन्हें 'खुदाई खिदमतगार' की बजाय लाल कुर्तीवाला कहना शुरू कर दिया।

१८-१९ अप्रैल, १९३० को २९० लाल कुर्तीवालों की प्रथम बैठक उन्होंने उतमान जई में की और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए २३ अप्रैल को सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, तब से लाल कुर्तीवालों की सभी जगह चर्चा होने लगी। अवज्ञा आंदोलन को पेशावर में भी जाग्रत करने के लिए गफ्फार खां जब नाकी थाना पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिए गये। लेकिन पुलिसवाले उस समय दंग रह गये, जब उन्होंने देखा कि गफ्फार खां की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्र सैकड़ों लाल कुर्तीधारियों ने जमीन पर बैठकर धरना दे दिया और बेंत-प्रहार बिना उफ किये सहते रहे।

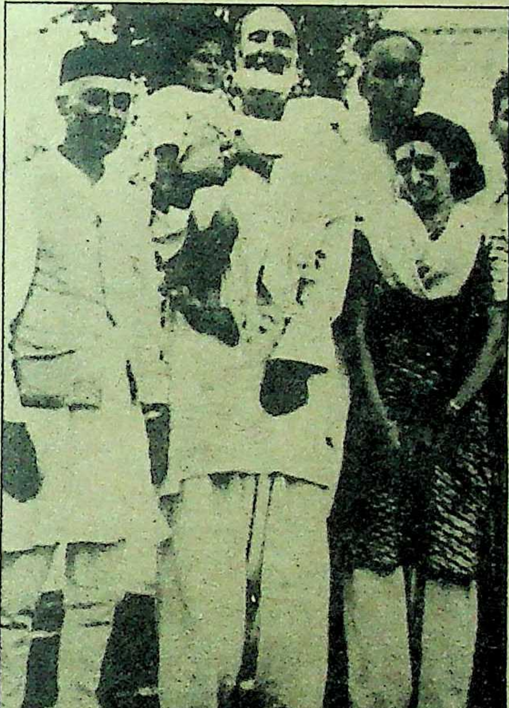

संघर्ष के प्रतीक : नेहरू, खां और इंदिरा गांधी

गफ्फार की गिरफ्तारी के १९ दिन बाद ही १३ मई, १९३० को सेना की एक टुकड़ी ने उतमान जई को चारों ओर से घेर लिया और सारे लाल कुर्ती वालों को गिरफ्तार करके उन्हें लाल कपड़े उतारने का हुक्म दिया, लेकिन 'प्राण रहते नहीं उतारूंगा' कहने पर बंदूक के कुंदों से मार-मार कर उन्हें बेहोश कर दिया गया। कुछ को उनके घरों की ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। लहूलुहान बेहोश खिदमतगारों के शरीर से सैनिकों ने लाल कपड़े उतार कर उनकी वहीं होली जला दी।

जेल से रिहाई के बाद, खिलाफत कमेटी की दो-मुंही एवं हिंदुओं के प्रति विद्वेष व अलगाव की नीति से दुखी गफ्फार खां सभी खुदाई खिदमतगारों के साथ खिलाफत कमेटी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गये और करांची के कांग्रेस अधिवेशन में वह लाल कुर्तीधारियों के साथ शामिल हुए। पंडित नेहरू ने पेशावर कांग्रेस कमेटी को कार्यालय-खर्च के लिए दी जानेवाली ५०० रुपए की धनराशि को बढ़ा कर जब १००० रुपए कर दिया तो गफ्फार खां बोले, "यह क्या कर रहे हैं आप। अगर आप हमारी मदद ही करना चाहते हैं तो लड़कियों का कोई स्कूल, छोटा-मोटा अस्पताल खुलवा दीजिए। इससे हमारी ज्यादा मदद होगी।"

करांची अधिवेशन से वापस लौट कर उन्होंने पुनः जनसंपर्क के लिए दौरा शुरू किया। उनके बढ़ते प्रभाव से आतंकित वायसराय लार्ड विलिंगडन ने जब उनकी गिरफ्तारी के बारे में गांधी जी से बात की तो उन्होंने (गांधीजी) कहा, "ऐसे में गांधी—इर्विन पैक्ट टूट जायेगा, फिर सारी जिम्मेदारी आपकी होगी।" कुछ दिनों बाद गांधीजी ने अंग्रेजों के खतरनाक इरादे को भांप कर गफ्फार खां को अपने पास बारडोली बुला लिया।

७ दिसंबर, १९३४ को उन्हें पुलिस ने पुनः गिरफ्तार कर लिया। १५ दिसंबर को उन्हें २ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी गयी। इस दौरान वह काफी बीमार रहे। उनका वजन १६८ पौंड से घटकर १४९ पौंड रह गया। उनकी गंभीर होती स्थिति से चिंतित सरदार पटेल ने उन्हें फ्रंटियर पंजाब फिर नासिक जेल में स्थानांतरित करने, उनकी सजा घटाने के लिए काफी भाग-दौड़ की, होम मेंबर सर हेनरी क्रेक से संपर्क भी किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फलतः गांधीजी ने अथक प्रयास किया और अंततः उन्हें "ए" श्रेणी दिलाने तथा पेशावर से पठान बावर्ची भिजवाने की अनुमति दिलाने में सफल हो गये। अंग्रेज अधिकारियों ने जान-बूझकर पठान बावर्ची के रूप में जिस व्यक्ति को उनके पास भेजा वह वस्तुतः टी०बी० का गंभीर मरीज था। अधिकारियों ने सोचा कि गफ्फार खां भी टी०बी० के शिकार हो खुद ही खतम हो जायेंगे।

सजा खतम होने पर वह वर्धा चले आये, क्योंकि सीमांत-प्रांत में उनके प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को २९ दिसंबर, १९३७ तक के लिए और बढ़ा दिया गया था। छह अगस्त, १९३८ को प्रतिबंध उठने पर छह वर्ष बाद उन्होंने फ्रंटियर प्रांत में प्रवेश किया। वहां की मूल समस्याओं को समझने के लिए खुद गांधीजी भी फ्रंटियर प्रांत गये।

गिरफ्तारियों का दौर: विश्वयुद्ध के दौरान सरकार को धन-जन की सहायता को लेकर अब आंदोलन छिड़ा और ८ अगस्त, १९४२ को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब पिकेटिंग से लेकर सत्याग्रह के अभियान तेज हुए तो गफ्फार खां को भी कई बार गिरफ्तार किया गया और हर बार उन्हें जेल ले जाने के बजाय पेशावर ले जाकर छोड़ दिया जाता रहा। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर इस्कंदर मिर्जा ने, जो बाद में स्वतंत्र पाकिस्तान के 'लौह राष्ट्रपति' के रूप में प्रसिद्ध हुए, गफ्फार खां के सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए हर कूटनीतिक प्रयास किये और उनके निर्देश पर सईद अकबर नामक एक खुदाई खिदमतगार को इतना

सीमांत गांधी

एक गुजरती सदी की उखड़ती सांसें

९७ वर्षीय सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे हैं। भारतीय उप महाद्वीप का एक शताब्दी पुराना यह प्रकाश पुंज किस दिन बुझ जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता।

बादशाह खां की जिंदगी अपने आप में संघर्ष, बलिदान, अहिंसा, शांति, सादगी, मोहब्बत तथा गरीबों, शोषितों की सेवा की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने जीवन भर सांप्रदायिक एकता-सौहार्द्र, भाई-चारे के लिए कार्य किया तथा महात्मा गांधी की तरह हमेशा पद और सत्ता से दूर रहे। इसीलिए उन्हें सीमांत प्रांत का गांधी करार दिया गया।

बादशाह खां ने कितने कष्ट और यातनाएं भोगीं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आजादी से पहले लगभग १५ वर्ष ब्रिटिश सरकार की जेलों में और आजादी के बाद लगभग १५ ही वर्ष पाकिस्तान सरकार की जेलों में बिताये। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुलिस लाठी चार्ज से उनकी तीन पसलियां टूट गयी थीं और एक फेफड़ा जख्मी होकर बाद में बेकार हो गया था। काफी समय तक उन्हें दिल और गुर्दे की भी तकलीफ रही जिसका उन्होंने भारत के अलावा ब्रिटेन, सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया में भी इलाज कराया।

खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म १८९० में अविभाजित भारत के पेशावर जिले की चरसद्दा तहसील के उतमानजई गांव में हुआ था। उनके पिता खान बहराम खां एक सम्मानित व्यक्ति थे और १८५७ के गदर में सराहनीय सरकारी सेवा के लिए अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी जागीरें बख्शीश में दी थीं। किंतु १९१९ में रौलेट कानूनों के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।

बादशाह खां ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने घर और एक मौलवी के मकतब में पायी। इसके बाद वह पेशावर के एक मिशन स्कूल में पढ़े। जब उनकी मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही थीं, तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, छह फुट तीन इंच की लंबी काठी और अन्य गुणों को देखते हुए उन्हें सेना में कमीशन देने की पेशकश की गयी। अगले दिन परीक्षा देने के बजाय वह भर्ती अधिकारी के पास चले गए। उन्हें तुरंत सेना में ले लिया गया। किंतु कुछ दिन बाद उन्होंने सेना के एक जूनियर ब्रिटिश अधिकारी को एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी का अपमान करते हुए देखा, तो उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि सेना की नौकरी छोड़ दी।

इसके बाद वह अलीगढ़ पढ़ने गये। वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद के साप्ताहिक अखबार 'अल हिलाल' को नियमित रूप से पढ़ते थे। इससे उनमें देश भक्ति की भावना का संचार हुआ।

१९११ में अलीगढ़ से पेशावर लौटने के बाद वह तुरंगजई के हाजी के संपर्क में आये। हाजीजी सीमांत प्रांत में राष्ट्रीय शिक्षा की मशाल जला रहे थे। गफ्फार खान भी इस अभियान में शामिल हो गये और उन्होंने सीमांत प्रांत में जगह-जगह राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

बादशाह खां ने राष्ट्रीय राजनीति में १९१९ में तब कदम रखा जब देश भर में रौलेट कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। उन्हें एक सभा में रौलेट कानूनों की कड़ी निंदा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद वह रिहा हो गये।

१९२० के शुरू में बादशाह खां ने दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली भाइयों, हकीम अजमल खान आदि ने संबोधित किया था। इसी वर्ष सीमांत प्रांत में प्रांतीय खिलाफत कमेटी गठित हुई और बादशाह खान उसके अध्यक्ष बने। दिसंबर १९२० में पेशावर में न्यू फ्रंटियर कांग्रेस गठित हुई और खिलाफत कमेटी ने उसके साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा लिया।

बादशाह खां ने अपने गांव में एक राष्ट्रीय हाई स्कूल खोला और अंजुमने-इस्लाह-उल-अफगानिया (अफगान सुधार सोसायटी) संस्था बनायी। अंग्रेजों को उनकी ये गतिविधियां पसंद नहीं आयीं और १७ दिसंबर १९२१ को उन्हें गिरफ्तार कर तीन वर्ष तक जेल में रखा गया।

इस बीच १९२३ में उनकी मां का निधन हो गया।

१९२६ में वह अपनी बड़ी बहन दूसरी बीवी और दो बच्चों को साथ लेकर हज पर मक्का गये। कुछ समय बाद जब वह बेत-उल-मुकद्दस में थे, तो वहां सीढ़ियों से फिसलकर उनकी दूसरी बीवी चल बसीं। दूसरी बीवी से उनके दो बच्चे हुए। एक लड़का—अब्दुल अली और दूसरी लड़की—मेहरताज।

मई १९२८ में बादशाह खान ने 'पख्तून' पत्रिका निकालनी शुरू की और उसके मानद संपादक रहे। गांधीजी के 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' की तरह यह पत्रिका भी पख्तूनों और विदेशों में बहुत लोकप्रिय हुई। पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद 'पख्तून' के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

१९२९ में बादशाह खान ने अपने गांव उतमानजई में एक सम्मेलन बुलाया और भारत की आजादी के ध्येय को लेकर 'अफगान जिरगा' के नाम से एक नयी पार्टी गठित की। बाद में कुछ समय तक इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम भी किया।

दिसंबर १९२९ में गफ्फार खान अपने कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। वहां से लौटकर उन्होंने पख्तूनों में देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा करना शुरू किया।

इसी लक्ष्य को लेकर जनवरी १९३० में बादशाह खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन किया। इस के कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने लाल कुर्ती पहनने का प्रावधान किया था जिससे वे 'लाल कुर्ती धारी' कहलाये। इस संगठन में सेना जैसा अनुशासन था और इसके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कर्नल और कमांडर जैसे नाम दिए गए थे। बैंड की धुन पर कार्यकर्ता पंक्तिबद्ध होकर देशभक्ति का तराना गाते हुए चलते थे। मार्च १९३० में इसकी सदस्य संख्या लगभग दो हजार थी। अंग्रेजों ने इसे सोवियत संघ के इशारे पर बना कम्युनिस्ट संगठन कहकर इसके प्रति दमनकारी रवैया अपनाया। इससे सीमांत प्रांत में यह संगठन आग की तरह फैल गया। सितंबर में इसकी सदस्य संख्या ८० हजार तक और अगले वर्ष १९३१ में लगभग तीन लाख पहुंच गयी। अगस्त १९३१ में इसके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गये थे। इतिहासकार मानते हैं कि यदि खुदाई खिदमतगार संगठन ने कांग्रेस के साथ मिलकर कुर्बानी नहीं दी होती, तो अगस्त १९४७ में भारत-पाकिस्तान को आजादी नहीं मिल पाती।

अक्तूबर १९३४ में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में उनसे अध्यक्षता करने की पेशकश की गयी, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि वह पार्टी के एक सिपाही की तरह ही काम करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के आग्रह पर वह कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और अ०भा० ग्रामीण उद्योग संघ की कार्यकारिणी के सदस्य अवश्य बने।

बादशाह खां के कांग्रेस से जुड़ने के कारण मुस्लिम लीग ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। बादशाह खां भी मुस्लिम लीग की धर्मांधता और पृथकतावादी नीति के कट्टर विरोधी थे। उनका सपना था पूरा हिंदुस्तान आजाद हो और हिंदू तथा मुसलमान भाई-भाई की तरह एक साथ रहें। इसलिए १९४६-४७ में भारत-ब्रिटिश वार्ता के दौरान उन्होंने विभाजन का जबर्दस्त विरोध किया। कांग्रेस ने जब तीन जून १९४७ को लार्ड माउंटबेटन की भारत-विभाजन की योजना स्वीकार कर ली, तो उन्हें और गांधी जी को मर्मांतक ठेस लगी। गफ्फार खां उस समय भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे किंतु उनसे सलाह तक नहीं ली गयी। यह गम गफ्फार खान को जीवन भर सताता रहा।

मार्च १९४८ में उन्होंने पाकिस्तान की संसद को संबोधित करते हुए सीमांत प्रांत और अपने संगठन खुदाई खिदमतगार को कायदे आजम जिन्ना को समर्पित कर दिया था, किंतु जिन्ना ने उनकी उपेक्षा करते हुए कहा कि वह अपने संगठन को मुस्लिम लीग में मिला दें। बादशाह खान इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने पख्तूनिस्तान की मांग उठायी। तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके संगठन को बुरी तरह कुचल दिया गया।

१९६२ में मानव अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बादशाह खां १९४८ से ही लगभग निरंतर जेल में हैं। उसने उन्हें उस वर्ष का कैदी (प्रिजनर आफ दि इयर) भी घोषित किया था।

१९६४ में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति दी। वहां से वह अफगानिस्तान चले गये जहां उन्होंने १९७२ तक स्व निर्वासित जीवन बिताया। इस बीच १९६९ में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर वह भारत आये, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वह १९८० में इलाज के लिए और १९८१ में श्रीमती इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर भारत आये थे।

—नरेश कुमार सिंह

पीटा गया कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। खिदमतगारों के शिविर में बननेवाले भोजन में उन्होंने खुफिया तरीके से जहर मिलवा दिया, जिससे कई लोगों की स्थिति गंभीर हो गयी। बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जा सका, फिर भी बाद में कुछ अपंग हो गये या नजरों की ज्योति खो बैठे।

इस्कंदर मिर्जा ने किराये के मुल्ला-मौलवियों को न केवल गफ्फार खां के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उभारा, बल्कि जब गफ्फार खां २९ अक्तूबर, १९४२ को मरदान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर धरना देने के लिए अपने साथियों के साथ पैदल रवाना हुए तो इस्कंदर मिर्जा के निर्देश पर पुलिस ने मीरवास डेरी में दल की बुरी तरह से पिटायी की। पुलिस इंसपेक्टर खुशदिल खां ने गफ्फार खां को लाठियों से इतना पीटा कि उनकी पसलियां टूट गयीं और वह खून से तरबतर हो गये, फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय मरदान जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद इंसपेक्टर जनरल (जेल) कर्नल स्मिथ के हस्तक्षेप पर उन पर मरदान, एबटाबाद आदि जेलों में होनेवाली थर्डडिग्री यातना कम हुई और उनके पुत्र वली खां को उनके साथ जेल में रहने की अनुमति मिली। लेकिन हरिपुर जेल (अक्तूबर, '४३) में फिर उन पर तथा उनके 'खुदाई खिदमतगार' साथियों पर जुल्म शुरू हो गया। रात ११-१२ बजे खिदमतगारों को जेल की कोठियों से खुले मैदान में कड़कड़ाती ठंड में निकाल कर बेंतों से निर्दयतापूर्वक पिटायी की जाती और गफ्फार खां को उन पर होते अत्याचारों को देखने के लिए विवश किया जाता ताकि घबड़ा कर वह आंदोलन वापस ले लें।

इस्कंदर मिर्जा को गफ्फार खां फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, इसीलिए जब वह स्वतंत्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और जैसे-जैसे सत्ता पर उनके पंजे जकड़ते गये वैसे-वैसे स्वतंत्र पाकिस्तान में उन पर दमन बढ़ता चला गया। मुस्लिम लीग की नीयत पर गफ्फार खां को शुरू से ही विश्वास नहीं था फिर पाकिस्तान के आजाद हो जाने पर गफ्फार खां तथा उनके लड़के गनी खां ने स्वतंत्र पख्तूनिस्तान की मांग की और गनी खां ने इसके लिए 'जल्मे पख्तून' संस्था की स्थापना कर सत्याग्रह छेड़ दिया। इस्कंदर मिर्जा के साथ-साथ मुस्लिम लीगी भी उनके दुश्मन बन गये। उन्होंने पख्तूनिस्तान की मांग कर रहे पठानों को दबाने का हर प्रयास शुरू कर दिया। दरअसल गफ्फार खां चाहते थे कि पख्तूनिस्तान का गठन भारत के अंतर्गत हो, लेकिन तत्कालीन वायसराय ने जनमत-संग्रह का अचानक फैसला कर उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। इसके लिए वह कतई तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अविभाजित भारत में हुए अंतिम चुनाव में उनकी पार्टी ने फ्रंटियर प्रांत में भारी बहुमत से विजय हासिल कर डा० खान के नेतृत्व में सरकार की स्थापना की थी।

जनमत-संग्रह का बहिष्कार : जनमत-संग्रह के प्रश्न पर जब अंतिम समय तक महात्मा गांधी एवं कांग्रेस-हाईकमान के बीच एकमत निर्णय नहीं हो सका तो गफ्फार खां ने ११ जून को जनमत-संग्रह के बहिष्कार का निर्णय दिया और खुद अकेले पाकिस्तानियों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया। ब्रिटिश अधिकारियों एवं लीगियों ने जनमत-संग्रह के दौरान लोगों को आतंकित करने के साथ-साथ जाली मतदान भी धड़ल्ले से कराया। खिदमतगारों के बहिष्कार, साम-दाम-दंड-भेद नीतियों के बावजूद वे ५०.१ प्रतिशत मत ही बटोर सके और इस तरह पख्तूनिस्तान की बात पर पूर्ण-विराम पूरी साजिश के बाद लग गया।

गफ्फार खां के अनुरोध पर (स्व०) नेहरू ने फ्रंटियर प्रांत का दौरा किया। ब्रिटिश अधिकारियों, लीगियों के इशारों पर उनकी यात्रा के दौरान वजीरियों, बदमाशों ने उन पर कई जगह हमला करने की कोशिश की लेकिन नेहरू के साथ चल रहे पठानों के कारण वे सफल नहीं हो सके।

१४ अगस्त को पाकिस्तान में जब जिन्ना सरकार ने शपथ ग्रहण की तो लीगियों के निर्देश पर फ्रंटियर के तत्कालीन गवर्नर सर जार्ज कनिंघम ने एक चाल चली। उन्होंने फ्रंटियर प्रांत के मुख्यमंत्री डा० खान को अपने शपथ-समारोह में बुलवाया, लेकिन उनको शपथ-ग्रहण करवाने के बजाय उनसे त्याग-पत्र की मांग की। उनके मना कर देने पर उनकी सरकार को अपदस्थ कर अब्दुल कयूम को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया।

पीपुल्स पार्टी का गठन : जिस तरह गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को तोड़ दिया जाये उसी तरह गफ्फार खां भी चाहते थे कि मुस्लिम लीग को तोड़ दिया जाये और अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां बनें। गफ्फार खां ने मार्च, '४८ में श्री सईद (सिंध) के साथ मिल कर पीपुल्स पार्टी का गठन किया तथा निश्चय किया कि 'खुदाई खिदमतगार' इस नयी पार्टी में बतौर स्वयंसेवक कार्य करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष गफ्फार खां चुने गये। पहले कई बार उन्होंने गांधीजी एवं नेहरूजी के अनुरोध पर भी कांग्रेस अध्यक्षता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बदली स्थितियों में उन्होंने पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष बनना उचित समझा।

उनके आंदोलन से आजाद पाकिस्तान की सरकार घबड़ा उठी। १५ जून, १९४८ को गफ्फार खां को कोहार में गिरफ्तार कर लिया गया और बिना एक बूंद पानी दिये उन्हें शाम तक रखा गया। बंदा दाऊर शाह से बन्नू जानेवाली सड़क पर स्थित एक रेस्ट हाउस में पुनः बाकायदे मुकदमे का नाटक हुआ और उन्हें तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। उनके साथ उनके दो साथियों को भी सजा दी गयी। आजाद पाकिस्तान में यह उनकी पहली गिरफ्तारी और पहली सजा थी। इसके बाद पुनः अंग्रेजों की तरह के जुल्म की दास्तान शुरू हो गयी।

पाकिस्तान सरकार ने पख्तूनों को कुचलने के लिए ८ जुलाई, १९४८ को नार्थ वेस्ट फ्रंटियर सरकार को एक अध्यादेश जारी कर उनके कानूनी

अधिकारों को छीन लेने तथा जेलों में भर देने का निर्देश दिया। अध्यादेश लागू होते ही ढाई हजार से भी अधिक खुदाई खिदमतगारों को बिना नोटिस दिये गिरफ्तार कर जेलों में भर दिया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया। जेल में बंद अपने साथियों के लिए प्रार्थना करने के लिए १२ अगस्त, १९४८ को गफ्फार खा की गिरफ्तारी के लगभग डेढ़ महीने के बाद, भारी सख्या में खुदाई खिदमतगार, मर्द-औरतें चार सद्दा के बबरा ग्राम में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। जब वे नमाज पढ़ रहे थे, अब्दुल कयूम के निर्देश पर वहां तैनात सैनिकों ने निहत्थे स्त्री-पुरुषों पर मशीनगनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दो हजार से भी अधिक लोग मारे गये। बहुतों की लाशें अंधे नाले में फेंक दी गयीं।

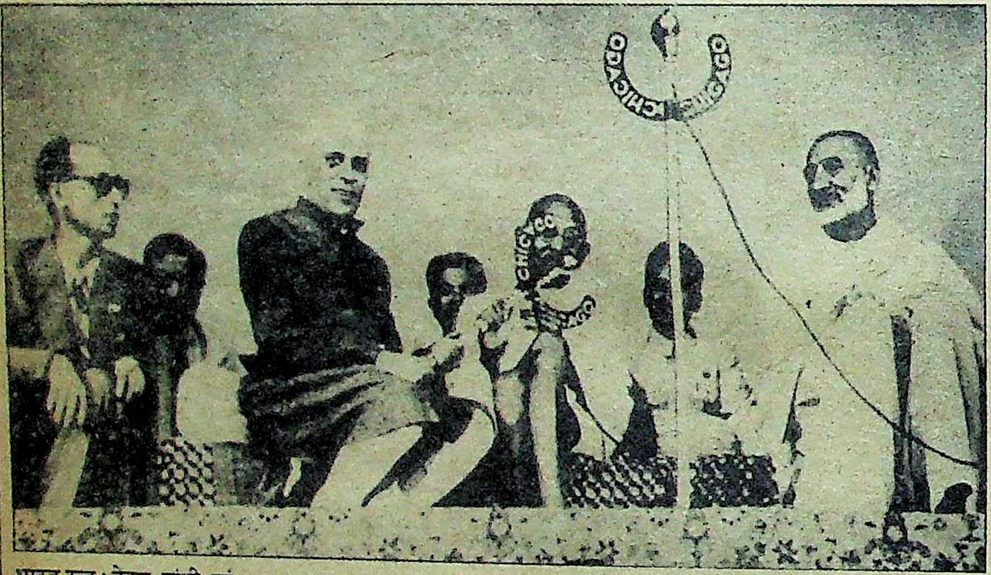
भारत रत्न : नेहरू, गांधी, खां

एक सप्ताह के भीतर डा० खान को गिरफ्तार कर उनकी संस्था को अवैध घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने संस्था के कार्यालय को जब्तकर तमाम कागजों-फाइलों को जला दिया। उधर गफ्फार खां की जेल में हालत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ पख्तून आंदोलन का समूल नाश करने पर पाकिस्तान सरकार तुली हुई थी। जब वह जेल में बंद थे, एक दिन (२२ अक्तूबर, १९५०) पाकिस्तान एयर फोर्स ने पख्तून गांवों पर यह कहकर बम बरसाये कि वहां घुस आये अफगानियों को भगाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। इस बमबारी में कम-से-कम सौ पख्तून मारे गये।

ब्रेनवाश की कोशिश : दूसरी तरफ जेल में गंभीर रूप से बीमार गफ्फार खां को मानसिक यातना दी जाती। तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के आदमी जेल में जाकर उनका ब्रेन वाश करने की कोशिश करते कि अगर आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जायें तो सरकार न केवल सारे प्रतिबंध हटा लेगी, बल्कि आपके बेटे और आपके आदमियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भी कर देगी। जब गफ्फार खां पर कोई असर नहीं हुआ तो तीन साल की सजा पूरी होने पर रिहा होते ही उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारियों एवं रिहाई का नाटक : अप्रैल, १९५२ में गफ्फार खां की हालत बहुत गंभीर हो गयी। जेलों में गंदे-सड़े भोजन के कारण उनके दांत खराब हो चुके थे, जिन्हें जेल डाक्टरों ने बड़ी निर्दयता से उखाड़ कर फेंक दिया। उनकी गंभीर स्थिति को लेकर जब समूचे विश्व में पाकिस्तान सरकार की कटु आलोचनाएं हुईं तो मेयो अस्पताल (लाहौर) में उनका लापरवाही से आपरेशन किया गया। आवश्यक दवाएं भी नहीं उपलब्ध करायी गयीं। विदेशों में आलोचना अधिक बढ़ जाने पर उन्हें रिहा करने का समाचार प्रकाशित-प्रसारित कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बहाने उन्हें मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कर सैनिकों के कब्जे में दे दिया गया, फिर कुछ समय बाद उन्हें सर्किट हाउस में स्थानांतरित कर नजरबंद कर दिया गया। किसी से भी मिलने या पत्र लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। काफी दिनों बाद, काफी प्रयास के बाद उन्हें रिहा किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बलूचिस्तान में प्रतिबंधात्मक आदेश भंग करने के जुर्म में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय तक बंद रख कर रिहा कर दिया गया।

लेकिन फिर वह ज्यादा दिन तक जेल से बाहर नहीं रह सके। १६ जुलाई, १९५५ को उतमान जई से ८ किमी० दूर शाहीबाग में गिरफ्तार कर उन्हें पेशावर ले आया गया। २४ जनवरी, १९५७ तक मुकदमे की तारीखें व स्थान (कभी लाहौर तो कभी पेशावर तो कभी कहीं) जानबूझ कर बदले जाते रहे, ताकि अधिक-से-अधिक दिन उन्हें जेल में बंद रखा जाये। २४ जनवरी १९५७ को लाहौर हाईकोर्ट के जज शब्बीर अहमद ने उन्हें अदालत उठने तक की सजा और १४ हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना देने से इनकार कर देने पर उनकी जायदाद कुर्क कर लेने का हुक्म दिया।

इस बार रिहाई के तीन दिनों बाद पाकिस्तान में छह विरोधी दलों के विलय से बनी पाकिस्तान नेशनल पार्टी में वह शामिल हो गये और पूरे पाकिस्तान का दौरा किया। ७ जुलाई को इस्कंदर मिर्जा ने राष्ट्रपति शांसन लागू कर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। १९५७-५८ तक गिरफ्तारियों और रिहाई का नाटक चलता रहा। अंततः ४ अप्रैल, १९५९ को उनके गिरते स्वास्थ्य, विश्वव्यापी आलोचनाओं को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया और वह उतमान जई चले गये। लेकिन उन पर १९६६ तक किसी भी निर्वाचन-प्रणालीवाली संस्था में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन १२ अप्रैल, १९६१ को उन्हें डेरा इस्माइल खां में गिरफ्तार कर लिया गया और पनियाला, सिंध हैदराबाद, मुलतान आदि जेलों में रखा गया। उनके साथ उनके दो हजार से भी अधिक साथियों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान की तमाम जेलों में ठूंस दिया गया। गफ्फार खां ने गंभीर बीमारी के बावजूद जेल में न केवल इलाज कराने से मना कर दिया बल्कि तीन दिन का अनशन भी किया। जब अधिकारियों को लगा कि उनकी किसी भी समय मौत हो सकती है तो उन्होंने ३० जनवरी, १९६४ को उन्हें रिहा कर दिया और भारत तथा दूसरे देशों के बढ़ते अनुरोध और दबाव पर सितंबर, १९६४ में उन्हें चिकित्सा के लिए इंग्लैंड जाने की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने उनकी चिकित्सा दिल्ली या बंबई में कराने की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया। लंदन में ही उनकी भेंट श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई जो उनसे मिलने के लिए विशेष रूप से वहां गयी थीं।

लंदन में उनका स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन वहां का मौसम उन्हें रास नहीं आया। तब डाक्टरों ने उन्हें केलिफोर्निया जाने की सलाह दी। लेकिन पाकिस्तान सरकार के निर्देश पर अमरीकी सरकार ने उन्हें कैलिफोर्निया या अमेरिका जाने का वीसा नहीं दिया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें बेरूत, तेहरान या काहिरा में कहीं इलाज कराने की छूट दी। वह काहिरा पहुंचे और उसके बाद अफगानिस्तान सरकार के आमंत्रण पर दिसंबर, १९६४ में वह काबुल पहुंच गये। अफगानिस्तान में रहकर भी सवा करोड़ पंख्तूनों की आजादी के लिए वह संघर्ष करते रहे। अंततः एक लंबे अरसे के बाद वह पुनः उतमान जई लौट गये—थके, हारे, बुढ़ापे तथा अनेक बीमारियों से जर्जर शरीर का बोझ लिए हुए। पाकिस्तान सरकार भी अंततः खामोश हो गयी—बूढ़े शेर को छेड़ने से अब कोई फायदा जो नहीं था, फिर उन्हें सारी जिंदगी जेलों में सड़ा सड़ा कर काफी बदनामी वह पहले ही ओढ़ चुकी थी।

गफ्फार खां उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन जिन पख्तूनों के लिए वह ताजिंदगी लड़े, यातनाएं सहीं, वे आज भी गरीब, असहाय और गुलाम हैं।

—रवींद्र श्रीवास्तव

मनोरमा

१५ सितम्बर' ८७

नववधु विशेषांक

नववधु-सा सुंदर-सजीला और अछूते विषयों को संजोये हुए हर नववधु के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भरी रचनाएं

प्रमुख आकर्षण

- अपने पति की प्रेमिका बनी रहिए
- पहला साल– नाजुक हाल
- चुम्बन: पहली रसभीनी पहचान
- कैसे होंगे आपके वो (राशि के अनुसार)
- सेक्स: कुछ घबराहट भरे प्रश्न
- नवदम्पतियों के लिए बेहतर परिवार-नियोजन
- पंच सितारा शादियां
- दुल्हन के जोड़े
- जेवर खरीदिए मगर सोच-समझ कर
- नयी-नयी गृहस्थन के लिए व्यंजन
- समाज के बदलते माहौल में अपनी बेटी को क्या सीख देना चाहेंगी आप?
- दुल्हन या चांद का टुकड़ा: रूप सज्जा दुल्हन की

आवरण कथा

कैसा होता है प्यार-सात फेरों के बाद?

विवाह, केवल एक नये जीवन की शुरुआत, नये-नये कपड़े, जेवर और पति के साथ शरीर का मिलन, रुमानी प्रेमाभिव्यक्ति ही नहीं है, एक परिपक्व व प्रगाढ़ लगाव की शुरूआत है, जो केवल गीत-संगीत की बुनियाद पर नहीं, वरन् रोज की जिंदगी जीने पर निर्भर करता है।

अन्य आकर्षण

- तलाश है एक कमाऊ पत्नी की
- जीवन साथी के लिए विज्ञापन देने का साहस कर सकेंगी?
- झूठ की बुनियाद पर सपने नहीं बनते
- क्या लड़के ही नहीं लड़कियां भी चाहती हैं दहेज?
- लड़का अच्छा है तो परिवार से क्या लेना-देना?
- संगीता गुप्ता की कहानी: एक चिट्ठी तुम्हारे नाम
- नरेन्द्र कोहली की पौराणिक कहानी: एषणा
- मुजफ्फर बुखारी का हास्य-व्यंग: नोक-झोंक

मूल्य-६.००

जीतू का कीर्तिमान !

धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की वापसी के कारण अब जब जीतेंद्र की पकड़ मद्रास तथा बंबइया फिल्म इंडस्ट्री पर ढीली होने लगी है, तो वह गिनीज बुक वालों का पता पूछते फिर रहे हैं। वह उन्हें बताना चाहते हैं कि समूचे विश्व में वही अकेले अभिनेता हैं, जिन्होंने २३ वर्षों में २५० से अधिक फिल्मों में नायक की भूमिकाएं निभायी हैं। वह एकमात्र नट-सम्राट हैं, जिनकी 'सेलेबेलिटी' का पताका समूची दुनिया में एक साथ लहराता रहा—दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक तथा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म निर्माता तो मुंहमांगी कीमत देकर उनकी फिल्में खरीदते रहे। वह तीन बार, फिल्मों से आउट होने पर (१९६२, १९६७, १९७७) पुन: फिल्मों में वापस शांत थपेड़े की तरह आये और भीषण लहरों की तरह छा गये। इस दौरान नंबर-वन सुपर सितारों (शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन) की आंधी के बावजूद उनका सितारा पूरे जोर-शोर से चमकता रहा। उन्होंने जिस भी अभिनेत्री (राजश्री, बबीता, रेखा, श्रीदेवी, जयाप्रदा, भानुप्रिया आदि गिनाते हैं, वह) को छू दिया वह लोहे से पारस बन गयी। उन्होंने अनगिनत (वह कैलकुलेटर पर भी हिसाब नहीं लगा पाते) सौपतियों को लखपति और हजारपतियों को करोड़पति बना दिया और अब भी बनाने का दमखम रखते हैं (यह दूसरी बात है कि वह लाखों रुपये खुद के फिल्म निर्माण में बहाकर हजार भी नहीं बटोर पाते हैं) यह दमखम भला हालीवुड के किसी सितारे में रहा है (वह ग्रेगरी पैक, रिचर्ड बर्टन आदि दर्जनों का नाम लेते हैं) ! और अब लोहे से पारस बन गयी श्रीदेवी जब जीतू को भाव नहीं देती, भानुप्रिया उसकी चुंबकत्व-शक्ति से आकर्षित नहीं होती, जीतू की सहायता के लिए जयाप्रदा आ गयी है। इस समय दोनों के पास फिल्मों की संख्या धीरे-धीरे घटती जो जा रही है।

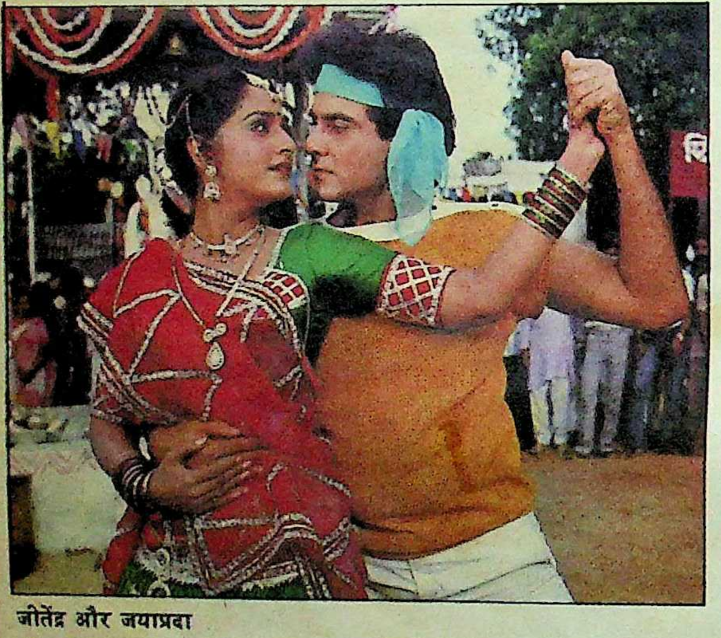

जीतेंद्र और जयाप्रदा

सुमित्रा का ग्लैमर

'रामायण' सीरियल की सुमित्रा उर्फ रजनीबाला शर्मा को वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक सभी रामायण-रचनाकारों के साथ-साथ रामानंद सागर से हमेशा शिकायत रही कि उन्होंने लक्ष्मण और भरत की मां सुमित्रा के साथ काफी अन्याय किया। रामायण (ग्रंथ और सीरियल दोनों) में उन्हें एक्स्ट्रानुमा बनाकर ही पेश किया। हिंदी और गुजराती की ३०० से भी अधिक फिल्मों में नायिका से लेकर चरित्र अभिनेत्री की विभिन्न भूमिकाएं निभा चुकी रजनीबाला के सामने, 'बुनियाद' की लाजोजी उर्फ अनीता कंवर की तरह, सुमित्रा की बन गयी पारंपरिक इमेज को तोड़ने की समस्या आ गयी हैं। और इसका उपाय भी उन्होंने लाजोजी की ही तरह ढूंढ़ निकाला है—वह फिल्मों में अंग-प्रदर्शन वाली ग्लैमरस भूमिकाएं स्वीकार करने लगी हैं। वह कहती हैं, "अगर आपके पास फिगर है और आपने उसे मेन्टेन रखा है तो फिर दिखलाने में क्या नुकसान! फिर शशिकलाजी ने जब 'फूल और पत्थर' में अति सेक्सी रोल किया तो उस समय उनकी उम्र मुझसे भी बहुत ज्यादा थी। हेलेन, जीनत अमान, रेखा—मुझसे छोटी थोड़े ही हैं...!" अब हेमामालिनी को संभल जाना चाहिए कि कहीं रजनीबाला उनका भी उदाहरण न दे दें।

दीप्ति नवल

रजनीबाला शर्मा

दीप्ति का नया रोग

दीप्ति भले इसे नहीं माने, लेकिन उनके कला फिल्मकार पति प्रकाश झा जरूर मानते हैं। जब शबाना आजमी, राजेश खन्ना से लेकर आशा सचदेव तक को यह शौक चर्राया है, तो भला ऐसे में दीप्ति क्यों पीछे रहें। कभी कविताएं लिखकर अपना मन बहलानेवाली दीप्ति नवल मानसिक रूप से बीमारों के लिए बड़े स्तर पर काम करने की योजना बना रही हैं। वह इस रोग पर व्यापक शोध के लिए अनुसंधान केंद्र, मानसिक रोगियों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने जैसे महत्वपूर्ण काम करना चाहती हैं और इसके लिए वह धन जुटायेंगी फिल्मों में काम करके। 'अनकही' में मानसिक रूप से विकलांग महिला की भूमिका निभाने के पहले वह कई मानसिक चिकित्सालयों में गयीं, रोगियों को देखा और तभी इस काम का निश्चय कर लिया। लेकिन समाज सेवा के पहले समाज के लिए, उपलब्ध होने की तो कोशिश कीजिए!

दे दे

सिप्पी की कसम अमिताभ का धरम

जब 'आखिरी रास्ता' के निर्देशक के० भाग्यराज को अमिताभ बच्चन ने 'लाडला' का डायरेक्टर बनाकर रमेश सिप्पी को वहां से निकाल दिया था, तो उन्होंने तभी निश्चय कर लिया था कि वह अमिताभ की जगह उसका विकल्प जरूर खड़ा करेंगे।

अमिताभ और मीनाक्षी 'शहंशाह' में

उन्होंने 'बुनियाद' के लेखक मनोहर श्याम जोशी से एक धांसू कथा लिखवायी और विनोद खन्ना को अमिताभ के मुकाबले खड़ा कर 'जमीन' की शुरुआत कर दी। 'जमीन' को वह एक साल के भीतर, लेकिन 'शोले' से भी बड़ी फिल्म बनाकर १९८८ में रिलीज कर देना चाहते हैं, ताकि १९८८ अमिताभ के लिए मुसीबत वर्ष बन जाये। सिप्पी की तरह लगभग एक दर्जन खार खाये निर्माता और भी हैं जो विनोद खन्ना को लेकर बड़े बजट की फिल्म बना कर १९८८ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। और-तो-और जिस के० भाग्यराज को वह 'लाडला' में ले आये वही 'लाडला' से पीछा छुड़ा कर जो नयी फिल्म बना रहे हैं उसमें अमिताभ की जगह विनोद को ले लिया है। सिप्पी ने 'शोले' से अमिताभ को नंबर वन स्टार तक पहुंचा दिया था, अब उन्होंने ही उन्हें जमीन सुंघाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब पता चला है अमिताभ रमेश सिप्पी से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि वह 'जमीन' रोक कर अगर 'आसमान' को शुरू कर दें, तो वह उन्हें मनचाही डेट्स दे देंगे और अपनी कीमत (बाजार-रेट) भी नहीं मागेंगे।

लेकिन रमेश 'आसमान' के बजाय 'जमीन' से ही जुड़ा रहना चाहते हैं।

छोरे तेरा [illegible]

किस-किस की खुदर्गाजयत

राकेश रोशन जबसे अभिनय की बागडोर जीतेंद्र, शत्रु और ऋषि कपूर को थमा कर निर्देशक बन गये हैं, उनकी पूछ और मांग अचानक बढ़ गयी है। अभिनेता के रूप में हमेशा 'सो-सो' रहनेवाले राकेश रोशन कभी श्रीदेवी व जयाप्रदा के 'गाड ब्रदरों' में समझे जाते थे। जयाप्रदा व श्रीदेवी राकेश को हमेशा निर्देशक बनने के लिए उकसाती रहीं कि उनके निर्देशन में बननेवाली फिल्म की नायिका वही होंगी। श्रीदेवी व जयाप्रदा को ध्यान में रख कर उन्होंने 'खुदगर्ज' की कहानी तैयार करायी, लेकिन अंतिम समय दोनों उन्हें ठेंगा दिखा गयीं, लेकिन राकेश ने बिना क्रिकेट के मैदान में गये ही एक धाकड़ बाउंसर मारा और उन दोनों की जगह भानुप्रिया और अमृता सिंह को लेकर फिल्म पूरी कर दी। श्रीदेवी और जयाप्रदा को उस समय और भी झटका लगा जब बिना फिल्म रिलीज हुए ही राकेश स्टार डायरेक्टर बन बैठे तथा भानुप्रिया को कई फिल्मों में साइन कर श्रीदेवी को ठेंगा दिखा दिया। अब श्रीदेवी और जयाप्रदा जरूर 'खुदगर्ज' का अर्थ समझ गयी होंगी।

राकेश रोशन, भानुप्रिया और अमृता सिंह के साथ

छाया: डी०आर० यादव

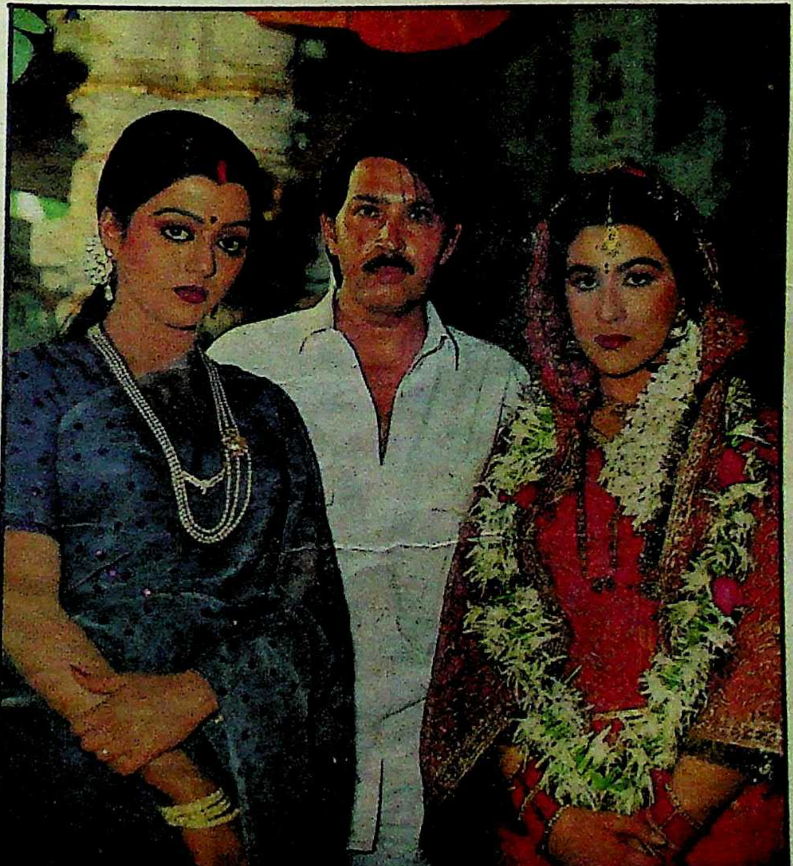

ऋषिकपूर और सोनम

नहले पर दहला

छह-छह सितारों को लेकर बड़े बजट की आलीशान फिल्में बनाने में माहिर निर्देशक-निर्माता यश चोपड़ा राजकपूर की तरह एक बार नये चेहरों (रोहण कपूर और फरहा) को लेकर फिल्म 'फासले' बनाने का शौक क्या पाल बैठे कि उनके और वितरकों के बीच का फासला बुरी तरह से बढ़ गया। अपने इस सपने को पालने में वह ऐसा हाथ जला बैठे कि दुबारा फिर सिर्फ नये सितारों के कंधे पर दांव रखने से हमेशा-हमेशा के लिए तौबा कर ली। अब वह जिस नयी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं,उसमें एक नयी लड़की (सोनम) को तो बतौर एक हिरोइन लिया है, लेकिन 'वक्त', 'दीवार', 'सिलसिला' आदि अपनी फिल्मों की तरह सितारों की भारी नुमाइश भी खड़ी कर दी है कि देखते हैं अब कैसे बिदकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरों के घोड़े हमारे अंगने आने से।

यों पूनम और फरहा, जिन्हें अपनी फिल्मों में उन्होंने पहली बार मौका दिया था, से यश चोपड़ा कुछ इस कदर नाराज हैं कि अभी से सोनम के सुपर स्टार बनने की भविष्यवाणी कर बैठे हैं।

लेकिन चालाक सोनम ने उनकी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने के बजाय अभी से घर पर हाजिरी लगाते निर्माताओं को 'ओबलाइज' करना शुरू कर दिया है उनकी फिल्में में साइन करके। यशजी, अब तो आपने नहले पर दहला कहावत का अर्थ समझ लिया होगा।

संजय सिंह की बगावत

संजय सिंह का कोई जनाधार नहीं : वीर बहादुर सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

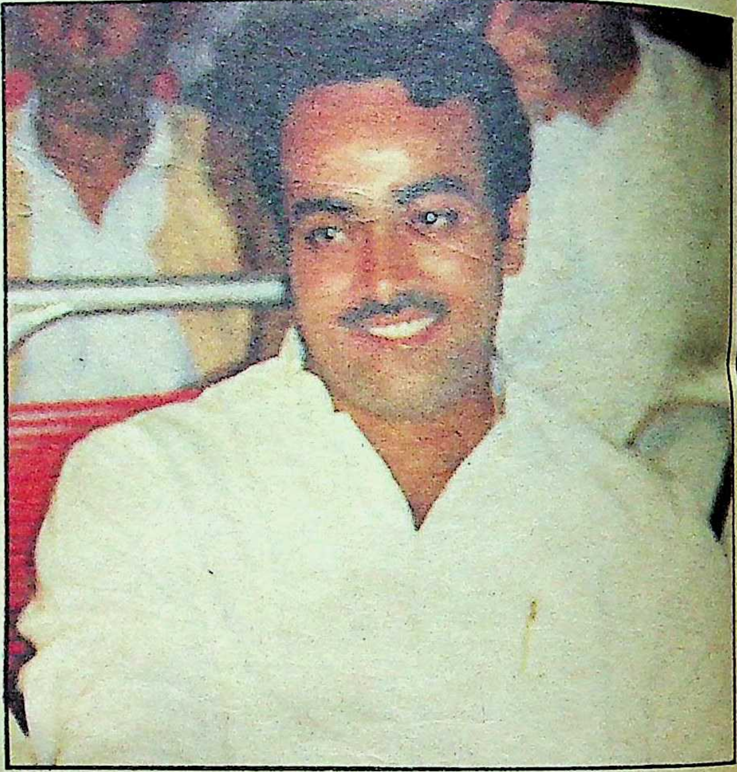

वीर बहादुर सिंह की हैसियत क्या है ? : संजय सिंह

२२ अगस्त को उत्तर प्रदेश के परिवहनमंत्री डा० संजय सिंह का अचानक इस्तीफा एक भारी राजनीतिक धमाका है। राजीव गांधी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अमेठी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय सिंह दो दिन पहले तक वीर बहादुर सिंह के खिलाफ अभियान अवश्य छेड़े हुए थे, लेकिन राजीव गांधी के प्रति वह अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इस्तीफा देते समय उन्होंने बजाय वीर बहादुर सिंह को निशाना बनाने के, राजीव गांधी को बनाया है। संजय सिंह अचानक राजीव गांधी के खिलाफ क्यों हो गये ? उनके त्यागपत्र के बाद अमेठी में राजीव गांधी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अभी तक उनका निशाना वीर बहादुर सिंह थे, लेकिन संजय सिंह ने २२ अगस्त को मझ दोपहर जब इस्तीफा दिया, तो उनकी तोप का मुंह राजीव गांधी की ओर था। "मैं नहीं समझता कि राजीव गांधी को देश का नेतृत्व करने का अब और मौका दिया जाये"—यह दो दिन पहले राजीव गांधी के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त करने वाले संजय सिंह का कहना था। इस अचानक हृदय परिवर्तन के बारे में संजय सिंह ने 'माया' को बताया, "दरअसल ऐसा अहम फैसला लेना आसान नहीं था। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि बोफोर्स की दलाली और अवैध धन के विदेशी बैंकों में जमा करने के मामले पर चुप्पी साधना देश के हितों का सौदा करना है, जो कोई भी देशभक्त नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने अपना दामन छुड़ाना ही उचित समझा।"

जोर आजमाइश : पिछले दो महीने से वीर बहादुर सिंह और संजय सिंह में दिल्ली पहुंच कर अपनी-अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने की प्रतियोगिता जारी थी। इसी बीच ७ अगस्त को मैनपुरी बस दुर्घटना हो गयी और मुख्यमंत्री तथा उनके परिवहन मंत्री संजय सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गयी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दुर्घटना इसलिए हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने चार साल से पुल का निर्माण नहीं होने दिया। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने संजय सिंह पर लापरवाही और परिवहन मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। १४ अगस्त को वीर बहादुर सिंह और संजय सिंह दोनों दिल्ली में जमे थे, लेकिन किसी की मुलाकात राजीव गांधी से नहीं हुई। इसके बाद आता है २० अगस्त का निर्णायक दिन। उस दिन राजीव गांधी का जन्म दिन था। १८ अगस्त की शाम की फ्लाइट से संजय सिंह दिल्ली पहुंचते हैं। दूसरे दिन १६ अगस्त को मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ धमकते हैं। उस दिन ५ मिनट मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से बातें हुईं, शेष समय वह संसद के केंद्रीय कक्ष में पार्टी के सांसदों से मंत्रणा करते रहे।

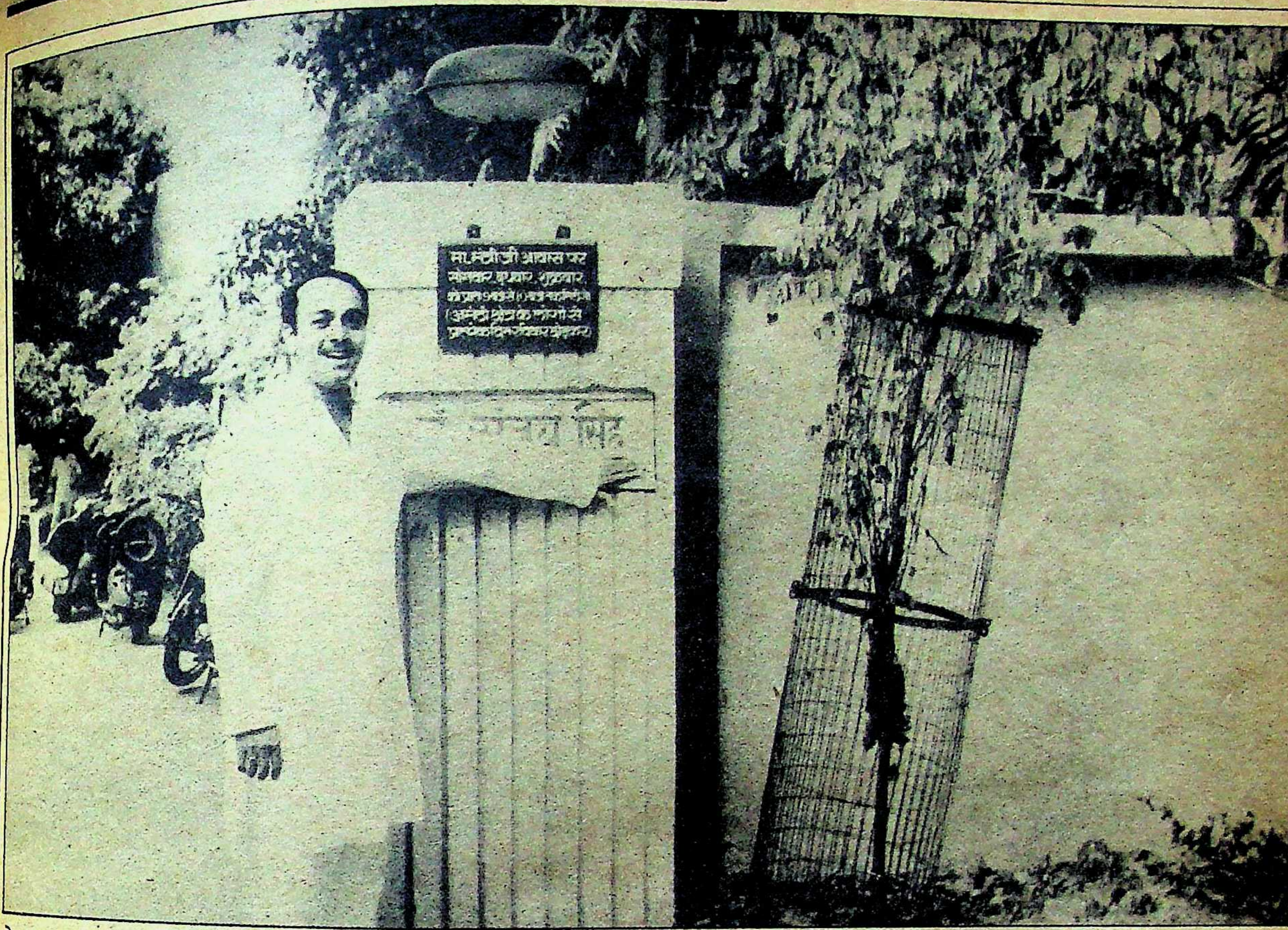

मेरा नाम काफी है: पद-नाम को ढंक कर खड़े संजय सिंह

बताया जाता है कि २० अगस्त को संजय सिंह ने काफी कोशिश की कि उनकी प्रधानमंत्री से बातें हो जायें, लेकिन बातचीत का समय नहीं मिला। अंततः संसद के द्वार पर उनका राजीव गांधी से आमना-सामना हुआ। बातें क्या हुईं, यह तो स्वयं संजय सिंह भी नहीं बताते, लेकिन यह जाहिर है कि राजीव गांधी ने वीर बहादुर के खिलाफ उनके अभियान पर नाराजगी जाहिर की, जबकि संजय सिंह अपनी बात पर डटे रहे कि वीर बहादुर जो कुछ कह रहे हैं, वह गलत है। उत्तर-प्रदेश के एक मंत्री का कहना है कि राजीव गांधी ने संजय सिंह को देखते ही कहा था, "दिस इज वैरी बैड।" इस पर संजय सिंह ने कहा कि मैं आपसे विस्तार से बातें करना चाहता हूं। बताया जाता है कि राजीव गांधी ने २१ अगस्त को मिलने के लिए कहा, लेकिन संजय सिंह से वह मिले नहीं। यह बात स्वाभिमानी संजय सिंह को बरदाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसी समय निर्णय कर लिया कि अब राजीव गांधी और उनके रास्ते अलग-अलग हैं।

सूत्रों का कहना है कि इसके बाद २१ अगस्त को संजय सिंह की विश्वनाथ प्रताप सिंह से लंबी बातचीत हुई और वहीं इस्तीफे का मजमून तैयार हुआ। राजा के कहने पर ही संजय सिंह ने बजाय वीर बहादुर सिंह को अपना निशाना बनाने के, सीधे-सीधे राजीव गांधी को लक्ष्य बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर उछले घोटालों का हवाला देते हुए जनहित एवं राष्ट्रहित में इस्तीफा देने की योजना बनी।

उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का कहना है कि राजीव गांधी तक यह खबर पहुंच गयी थी कि संजय सिंह को २० अगस्त को अपने इस्तीफे की घोषणा उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जामंत्री सुनील शास्त्री द्वारा उन्नाव में आयोजित सभा में करनी थी। सुनील शास्त्री ने राजीव गांधी हटाओ अभियान के तहत हर दसवें दिन एक सभा आयोजित करने की योजना बनायी है। २० अगस्त को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म-स्थली उन्नाव में इस योजना की शुरुआत सभा थी। दिल्ली में व्यस्त रहने के कारण संजय सिंह इस सभा में नहीं पहुंच सके।

इस्तीफा या बर्खास्तगी: संजय सिंह को अंतिम निर्णय की ओर अग्रसर करने में वी॰पी॰ सिंह के १९ अगस्त के बरेली दौरे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन बरेली की रैली में कांग्रेस-इ के २३ असंतुष्ट विधायक पहुंचे थे। इसी रैली में राजा ने आह्वान किया था कि कांग्रेसी विद्रोह करें। ऐसी स्थिति में संजय सिंह और इंतजार नहीं कर सकते थे।

जब २० अगस्त को संजय सिंह को राजीव गांधी में कोई आस्था नहीं रही, तो २१ अगस्त को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सलाह पर वह बजाय वीर बहादुर की खिलाफत के, राजीव गांधी की भर्त्सना करते हुए इस्तीफे के लिए तैयार हो गये। २२ की सुबह वह दिल्ली से लखनऊ आये। उनके साथ आरिफ मोहम्मद खान भी थे। २२ अगस्त को उन्होंने लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर साढ़े बारह बजे के करीब पत्रकारों को बुलाया और अपने इस्तीफे का धमाका कर दिया। उस समय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। इस्तीफे की खबर सुनते ही वह दो बार प्रधानमंत्री से मिले।

२२ अगस्त की शाम को जब मुख्यमंत्री लखनऊ लौटे, तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह को इस्तीफा देने से पहले ही अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण बरखास्त किया जा चुका है। वैसे संजय सिंह ने साढ़े बारह बजे इस्तीफा दिया था और इसकी प्रतिलिपि उन्होंने तुरंत राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यालयों में भेज दी थी। बरखास्तगी और पार्टी से ६ साल के लिए निकाल देने के समाचार बाद में आये। लेकिन दूरदर्शन और रेडियो ने इस्तीफे के बजाय, बरखास्तगी के ही समाचार दिये। वैसे भी मुख्यमंत्री की यह शैली बन गयी है कि वह इस्तीफे की अपेक्षा बरखास्त करने को तरजीह देते हैं। सुनील शास्त्री और जफरअली नकवी ने भी इस्तीफे दिये थे, लेकिन बजाय इस्तीफे

फिर उसी तरह का संघर्ष करने की योजना : संजय सिंह की पहली गिरफ्तारी

मंजूर करने के, उन्होंने उनको बरखास्त करना श्रेयस्कर समझा था। वही स्थिति संजय सिंह के मामले में हुई है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि संजय सिंह के हट जाने से पार्टी और उनकी सरकार पर क्या असर पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा, "संजय सिंह की हैसियत ही क्या है? वह पांच सितारा संस्कृति के राजनेता हैं। उनका गरीबों से नाता ही क्या है? वह उस षड्यंत्र के हिस्सा हैं जो राजीव गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। संजय सिंह की बरखास्तगी से दल के अन्य सदस्यों को यह पता चल जायेगा कि नेतृत्व की अहमियत क्या है।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल्दी ही संजय सिंह के भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने आ जायेंगे। ठीक ऐसी ही बातें संजय सिंह कह रहे हैं (देखिए साक्षात्कार)।

बहरहाल संजय सिंह जिस तरह से अपने एक दशक के राजनीतिक जीवन में सशक्त राजनेता के रूप में उभरे हैं, उसको देखते हुए उनके इस इस्तीफे के दूरगामी परिणामों से नकारा नहीं जा सकता। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, राजीव गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से उनका विधायक होना। वह दो बार यहां से सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं। अकेले अमेठी क्षेत्र से राजीव को भी लगभग आधे विजयी मत प्राप्त हुए थे। संजय सिंह से मुंह मोड़ लेने का निर्णय राजीव गांधी के लिए आसान नहीं था। लगता है उन्होंने अब यह संकल्प कर लिया है कि असंतुष्टों के दबाव के आगे वह बिलकुल नहीं झुकेंगे और इसी संकल्प को जगजाहिर करने के लिए उन्होंने संजय सिंह से नाता तोड़ लेने का निर्णय लिया है। यदि संजय सिंह के राजनीतिक अतीत को देखें, तो एक बात साफ है कि वह शुरू से ही महत्वाकांक्षी रहे हैं, इसीलिए वह अपने समकक्ष लोगों की आंखों में हमेशा खटकते रहे हैं। यद्यपि वह इस बात से इनकार करते हैं कि वह मुख्यमंत्री-पद के दावेदार रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि राजनीति में प्रवेश के समय से ही वह इस पद के आकांक्षी रहे हैं।

संजय सिंह का राजनीति-प्रवेश : संजय सिंह का राजनीति में प्रादुर्भाव जहां संजय गांधी की कृपा से हुआ था, वहीं एक समय में वीर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश में संजय गांधी के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति थे। वर्ष १९७५ में संजय गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की तलाश शुरू हुई थी, जहां से अगले चुनाव में संजय गांधी आसानी से मैदान जीत सकें। अमेठी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था। रायबरेली से यह सटा हुआ था। मां-बेटे अगल-बगल रहेंगे, यही सोचकर अमेठी को संजय गांधी का कार्यक्षेत्र बनाया गया था।

उन्हीं दिनों संजय गांधी ने पांच सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा करते हुए पहला श्रमदान शिविर अमेठी में आयोजित किया था। उस समय वीर बहादुर सिंह, राजस्वराज्यमंत्री थे। उनके कैबिनट मंत्री स्वामी प्रसाद सिंह थे। स्वामी प्रसाद ने अपने राज्य मंत्री को ठीक उसी तरह कोई अधिकार नहीं दे रखा था, जैसे आज वीर बहादुर सिंह मंत्रिपरिषद के राज्यमंत्री अधिकारहीन हैं।

चूंकि वीर बहादुर सिंह, संजय गांधी के नजदीक पहुंच चुके थे, इसलिए अमेठी के श्रमदान शिविर का इंचार्ज संजय गांधी ने उन्हें ही बना दिया था। उस समय संजय सिंह २२ साल के थे। अपने पिता राजा रणंजय सिंह के प्रभाव से वह युवक कांग्रेस में आना चाहते थे। अम्बिका सोनी युवा कांग्रेस की अखिल भारतीय अध्यक्ष थीं, जबकि राजेन्द्र सिंह सोलंकी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

संजय सिंह सुलतानपुर जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते थे। उस समय सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे केदारनाथ सिंह, इंदिरा-गांधी मंत्रिपरिषद में उपमंत्री थे। वी०पी० मौर्य, चन्द्रजीत यादव और केदारनाथ सिंह कांग्रेस के वामपंथी गुट में थे। इसी गुट की अम्बिका सोनी भी थीं। केदारनाथ सिंह नहीं चाहते थे कि संजय सिंह को सुलतानपुर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाये। इसीलिए उन्होंने कड़ा विरोध किया। नतीजतन केदारनाथ सिंह के एक चहेते मुस्लिम युवक को युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया गया।

वर्ष १९७७ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। श्रीमती गांधी और संजय गांधी की गतिविधियां कुछ समय के लिए ठण्डी पड़ गयीं। जून, १९७७ में उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए। संजय सिंह, अमेठी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। लेकिन केदारनाथ सिंह की सिफारिश पर टिकट मिला बैजनाथ सिंह को। इस चुनाव में नारायण दत्त तिवारी, गुलाब सेहरा और अरुण कुमार सिंह मुन्ना सहित केवल ४६ कांग्रेसी ही विधानसभा के लिए चुने जा सके थे, जबकि जनता पार्टी को ३५१ स्थानों पर सफलता मिली थी। हारने वालों में बैजनाथ भी थे।

वर्ष १९७८ में युवा कांग्रेस के प्रादेशिक अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना थे। संजय गांधी और नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध जनता सरकार ने कई आपराधिक मुकदमें चला दिये। लखनऊ और देहरादून की अदालतों में इन मुकदमों की सुनवाई हो रही थी। संजय गांधी यह चाहते थे कि मुकदमों की सुनवाई के दौरान युवक कांग्रेस के लोग अदालतों के बाहर नारेबाजी करके ऐसा दबाव-माहौल पैदा करें कि मामले वापस ले लिये जायें। लेकिन उस समय ज्यादातर कांग्रेसी भयभीत और हतोत्साहित थे। मुन्ना इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए पैसे और साधन की आवश्यकता थी, सरकार अपनी थी नहीं, इसलिए यह संभव नहीं था।

संजय गांधी को लगा कि विधायक बनने के बाद मुन्ना, युवा कांग्रेस में निष्क्रिय हो गये हैं। बस यहीं से उन्होंने ऐसे आदमी की तलाश शुरू कर दी जो साधन जुटा सके। संजय सिंह को मुन्ना ने युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी में रखा था। कहते हैं, संजय

सिंह ने ही मुन्ना के खिलाफ संजय गांधी के कान भरे थे। नतीजतन, मुन्ना को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर संजय सिंह को उनके स्थान पर अध्यक्ष बना दिया गया।

उस समय तक संजय सिंह को भाषण आदि का अभ्यास नहीं था। राजसी ठाठ में पले राजकुमार को राजनीति में कोई परेशानी न हो, इसलिए संजय गांधी ने उनकी मदद के लिए जगदम्बिका पाल जैसे तेज-तर्रार युवक को युवा कांग्रेस का महामंत्री बना दिया। जगदम्बिका पाल ने संजय सिंह का जिले-जिले में दौरा कराया। यही नहीं, जब भी संजय गांधी की लखनऊ या देहरादून में पेशी होती थी, जगदम्बिका पाल सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर अदालत के बाहर नारेबाजी कराते थे। यह बात दूसरी थी कि साधन और पैसा उपलब्ध कराने का काम संजय सिंह करते थे।

जनवरी, १९८० के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में लौट आयी। जिन राज्यों में जनतापार्टी की सरकारें थीं, वहां कांग्रेसियों ने सरकार हटाओ आन्दोलन शुरू किया। राजकुमार संजय सिंह ने पहली बार २३ जनवरी, १९८० को लखनऊ में विधान भवन के सामने हजारों इंकाइयों के साथ गिरफतारी दी।

मई १९८० के विधानसभा चुनाव में संजय गांधी ने अरुण कुमार सिंह मुन्ना का टिकट काट दिया। उन्होंने ढूंढ-ढूंढ कर अपने सर्मथकों को पार्टी टिकट दिये। इनमें वीर बहादुर सिंह, संजय सिंह, अकबर अहमद डम्पी, विद्याभूषण, आजाद कुमार कर्दम, देवेंद्र पाण्डेय, भोला पांडेय, राजकुमार भार्गव आदि मुख्य थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने जहां जनता पार्टी का सफाया कर ३०६ स्थानों पर कब्जा किया था, वहीं संजय सिंह, अमेठी विधानसभा क्षेत्र से ४६,६०३ मत प्राप्त कर पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतनेवाले व्यक्ति बने।

भविष्य दांव पर: संजय सिंह

दावेदारी : यहीं से संजय सिंह, उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी पाने के लिए अपने को सशक्त दावेदार मानने लगे। लेकिन डम्पी और वीर बहादुर यह कतई नहीं चाहते थे कि 'कल का छोकरा' मुख्यमंत्री बने। उधर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रदेश की बागडोर नारायण दत्त तिवारी (उस समय संसद सदस्य) के हाथों में सौंपने का मन बना चुकी थीं। ५ जून, १९८० को इंका विधानमंडल दल में नये नेता का चुनाव था। श्रीमती गांधी के निर्देश पर ही नारायण दत्त तिवारी ३ जून को दिल्ली से लखनऊ आ गये थे। 'मनोनीत नेता' के रूप में स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ था।"

लेकिन न तो वीर बहादुर, नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते थे और न ही संजय सिंह। इस मुद्दे पर दोनों एक हो गये। पार्टी में 'संजयवादियों' की तूती बोल रही थी। वीर बहादुर के कहने पर ही डम्पी, संजय सिंह, देवेंद्र पांडेय, श्यामलाल बाजपेई, आजाद कुमार कर्दम ने तिवारी को मुख्यमंत्री बनाये जाने का खुलेआम विरोध शुरू कर दिया। संजय वादियों ने आवाज बुलंद की—संजय गांधी को मुख्यमंत्री बनाओ।

देवेंद्र पांडेय ने ३ जून को ही दिल्ली में सार्वजनिक रूप से यह मांग की थी कि संजय गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और यदि संजय गांधी इसके लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं अपनी विधानसभा सीट उनके लिए खाली करने को तैयार हूं। उधर धर्मवीर ने भी श्रीमती गांधी से कहा था, "उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की समस्याएं केवल संजय गांधी ही हल कर सकते हैं।

इसी क्रम में ४ जून, १९८० को यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, "कांग्रेस विधान मंडल दल के हम सभी सदस्य सर्वसम्मति से संजय गांधी को विधान मंडल दल का नेता मानते हैं।" इस प्रस्ताव पर विधायकों के हस्ताक्षर कराने का अभियान शुरू हुआ। भला उस समय किसकी मजाल थी जो इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करता। तिवारी समर्थक चुप हो गये। पांच जून की बैठक में यह प्रस्ताव लोकपति त्रिपाठी को पेश करना था, जिसका समर्थन संजय सिंह को करना था। लेकिन ४ जून की दोपहर यह सूचना मिली कि बैठक एक दिन के लिए टल गयी है। दरअसल संजय गांधी का नाम मुख्यमंत्री-पद के लिए उछालने के पीछे वीर बहादुर की ही चाल थी, ताकि नारायण दत्त तिवारी का दावा कट जाये।

श्रीमती गांधी, नारायण दत्त तिवारी की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ८ जून को नारायण दत्त तिवारी को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और फिर अगले दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत कर लखनऊ भेज दिया।

एक नाटक: संजय सिंह, इस बात से खुश थे कि उनके श्वसुर (विश्वनाथ प्रताप सिंह की भतीजी की शादी संजय सिंह से हुई है) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए वह कैबिनेट मंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह और संजय गांधी दोनों ही संजय सिंह को मंत्री-पद नहीं देना चाहते थे। इसका एक कारण यह था कि अगर संजय सिंह को पद दिया गया, तो डम्पी को कैसे मनाया जायेगा। जब यह बात संजय सिंह को पता चली, तो वह काफी मायूस हो गये। उन्होंने संजय गांधी से काफी अनुनय-विनय की। नतीजतन, बीच का रास्ता निकाला गया।

तय यह हुआ कि ९ जून को शपथ-ग्रहण समारोह में संजय सिंह का नाम कैबिनेट मंत्री के रूप में पुकारा जायेगा, तब संजय सिंह मंच पर जाकर यह कहेंगे, "अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मंत्री पद लेने के बजाय पार्टी का काम देखूंगा।"

शपथ ग्रहण समारोह में यह ड्रामा बखूबी हुआ। संजय सिंह को यह उम्मीद थी कि देर-सबेर राजा साहब उन्हें मंत्री जरूर बनायेंगे। लेकिन अपनी छवि के प्रति हमेशा सचेत रहने वाले राजा मांडा ने संजय सिंह को कभी उठने नहीं दिया। हालांकि उस समय विपक्ष के एक प्रमुख नेता मोहन सिंह ने यहां तक आरोप लगाया था कि दामाद होने के नाते संजय सिंह तमाम महत्वपूर्ण फाइलें खुद देखते हैं।

राजा मांडा दो वर्ष तक (९ जून, १९८० से २८ जून, १९८२) तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसी बीच उन्होंने अब्दुल रहमान खां नश्तर, यशपाल सिंह जैसे मंत्रियों को तो गंभीर शिकायतों के कारण हटा दिया था, लेकिन चाहते हुए भी न तो वीर बहादुर सिंह को हटा सके और न ही उनका विभाग बदल सके।

वीर बहादुर सिंह ने राजा के विरुद्ध मंत्रियों का एक शक्तिशाली गुट बना रखा था। जिसमें बलराम सिंह यादव, विद्याभूषण, रणजीत सिंह जूदेव और बच्चा पाठक प्रमुख थे। शायद ही आज किसी को इस बात का विश्वास हो सकेगा कि संजय सिंह की राजा मांडा से कभी नहीं पटी। यही वजह थी कि राजा के विरोधी गुट में उस समय संजय सिंह भी शामिल थे।

वीर बहादुर सिंह हवा का रुख पहचानने में शुरू से ही माहिर हैं। संजय गांधी की मृत्यु के बाद जैसे ही अरुण नेहरू, राजनीति में शक्तिशाली हुए, वीर-बहादुर ने उनका दामन थाम लिया। राजा की शिकायतें वीर बहादुर, अरुण नेहरू के जरिये ऊपर तक पहुंचाते थे। कई बार राजा ने वीर बहादुर को मंत्री-पद से हटाने की अनुमति हाईकमान से मांगी, लेकिन अरुण नेहरू के प्रभाव के कारण वह सफल

नहीं हो सके।

अचानक २८ जून, १९८२ को राजा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाये, दिल्ली दरबार के सामने यह समस्या पैदा हो गयी। २० दिनों तक राजा कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। राजा की सलाह पर ही श्रीमती गांधी ने श्रीपति मिश्र को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया। १९ जुलाई, १९८२ को श्रीपति मिश्र ने मंत्रिपरिषद की शपथ ली। संजय सिंह पहली बार राज्यमंत्री के रूप में शामिल किये गये।

यह भी एक विडम्बना थी कि दो वर्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री का पद ठुकराने वाले संजय सिंह को राज्यमंत्री के पद पर ही संतोष करना पड़ा। श्रीपति के कार्यकाल में भी वीर बहादुर सिंह, शक्तिशाली मंत्री बने रहे। चूंकि संजय सिंह से अरुण नेहरू और अरुण सिंह दोनों ही नाराज थे, इसलिए उन्होंने वीर बहादुर सिंह से मिलकर चलना ही मुनासिब समझा।

उधर अरुण सिंह, उत्तर प्रदेश में अपना एक विश्वासपात्र व्यक्ति चाहते थे। उन दिनों वह संसदीय क्षेत्र के इंचार्ज थे। ब्लाक प्रमुख के चुनाव में जब अमेठी ब्लाक से इंका का उम्मीदवार हार गया, तो संजय सिंह के समतुल्य अरुण सिंह एक विश्वासपात्र ठाकुर की खोज में लग गये। संजय गांधी और संजय सिंह द्वारा सताये गये अरुण सिंह मुन्ना ने इसे एक अच्छा मौका समझा और लपककर अरुण सिंह का दामन थाम लिया। उन्हीं दिनों विधान परिषद की एक सीट रिक्त हुई थी। अरुण सिंह ने मुन्ना को न केवल विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया, वरन् ७ फरवरी, १९८४ को श्रीपति मिश्र ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करते समय मुन्ना को राज्यमंत्री बना दिया।

३ अगस्त को जब नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी संजय सिंह राज्य मंत्री ही रहे। दुबारा जब तिवारी ने

साक्षात्कार/संजय सिंह

राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकता हूं

माया : आप कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दिया है, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि परिवहन मंत्रालय का काम ठीक से न चलाने के कारण उन्होंने आपको बर्खास्त कर दिया है?

सिंह : वीर बहादुर ने कभी सच बोला है? यही बात तो उन्होंने सुनील शास्त्री और जफर अली नकवी के बारे में कही थी। वह कितना सच बोलते हैं, यह प्रदेश की जनता जानती है। मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। यदि वीर बहादुर के वश की बात होती, तो वह मुझे दो दिन भी टिकने नहीं देते। वीर बहादुर की हैसियत ही क्या है?

माया : आप तो वीर बहादुर के खिलाफ थे, लेकिन इस्तीफा आपने राजीव गांधी की भर्त्सना करते हुए दिया है। अचानक राजीव गांधी के प्रति आपकी आस्था क्यों समाप्त हो गयी?

सिंह : दरअसल कुछ समय से मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था। बोफोर्स दलाली और स्विस बैंक में अवैध धन जमा करने के मामले उछल रहे थे। राजीव गांधी की विश्वसनीयता बिलकुल समाप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि जब गंगोत्री ही प्रदूषित है, तो परनाला साफ करने से क्या होगा। मुझे लगा कि मैं यदि राजीव गांधी में निष्ठा बनाये रखता हूं, तो जनता के साथ धोखा और देश के साथ विश्वासघात होगा।

माया : क्या आपने इस्तीफा इसलिए दिया है कि आप वीर बहादुर सिंह को हटाकर स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यह बात कांग्रेस-इ अध्यक्ष को मंजूर नहीं थी?

सिंह : मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया। न मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि राजीव गांधी नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर रहे थे।

माया : क्या आप राजीव गांधी के जन्मदिन पर उनसे मिले थे?

सिंह : मिला था, लेकिन क्या बात हुई बताऊंगा नहीं।

माया : आपको ६ साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

सिंह : पार्टी हमारी थी और हनारी है। राजीव गांधी की पार्टी कहां से आयी? इसलिए मुझे पार्टी से निकालने वाले वह होते कौन हैं?

माया : क्या आपके साथ और लोग भी इस्तीफा देगें?

सिंह : देखते जाइये!

माया : आपके इस्तीफा देने से अमेठी संसदीय क्षेत्र में राजीव गांधी की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा?

सिंह : अमेठी हजार साल से हमारी है और हमारी रहेगी। जो कुछ हो रहा है उससे अमेठी की जनता दुखी है।

माया : आषकी राय में वीर बहादुर कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे?

सिंह : ज्यादा से ज्यादा दो माह।

माया : सुना है आप वीर बहादुर सिंह के कथित भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठे करने में लगे हैं?

सिंह : हां, ये भ्रष्टाचार उजागर होते ही जनता उन्हें पद छोड़ने के लिये बाध्य कर देगी।

माया : क्या अब आप विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनजागरण अभियान में साथ देंगे?

सिंह : पूरा-पूरा।

माया : आप यह कहते रहे हैं कि आप इस्तीफा देते नहीं, लेते हैं। फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया?

सिंह : यह बात मैंने वीर बहादुर के संबंध में कही थी। यह बात अब भी सही है, क्योंकि मैंने इस्तीफा वीर बहादुर सिंह के कहने पर नहीं दिया है और वीर बहादुर का इस्तीफा संघर्ष करके लिया जायेगा। जल्दी ही ९० विधायक वीर बहादुर का साथ छोड़ने वाले हैं।

माया : अब आपका अगला कदम क्या होगा?

सिंह : जनजागरण में जमकर भाग लूंगा और खासकर अमेठी में राजीव गांधी को उखाड़ फेंकने का अभियान शुरू करूंगा। यदि राजा (विश्वनाथ प्रताप सिंह) कहेंगे, तो अमेठी मे राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ूंगा?

मंत्रिपरिषद का विस्तार किया, तब संजय सिंह के साथ-साथ सुनील शास्त्री और अरुण कुमार सिंह मुन्ना को भी कैबिनेट मंत्री बनाया।

बढ़ता प्रभाव : मार्च, १९८५ में विधानसभा चुनाव में अमेठी क्षेत्र से संजय सिंह ने एक लाख २४ हजार मत प्राप्त कर पूरे देश में सर्वाधिक मतों से जीत का रिकार्ड कायम किया। सितम्बर, १९८५ में जब नारायण दत्त तिवारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केन्द्र में चले गये, तो संजय सिंह, मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार हो गये। लेकिन अरुण नेहरू की कृपा से कुरसी वीर बहादुर को मिल गयी। इसी के बाद से संजय सिंह ने वीर बहादुर के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी। ऐसे विधायकों को वह चुन-चुन कर अपने साथ करने लगे जो वीर बहादुर से नाराज थे। कैप्टन बल्देव सिंह, मोहम्मद असलम खां, जयदीप सिंह बरार, अफसर यू०अहमद, नेकचन्द्र पांडेय, प्रदीप माथुर, मुईद अहमद, सुखदा मिश्रा, रामप्रकाश सेंगर, भगवती चौधरी, हरीश वाजपेयी और हुकुम सिंह जैसे विधायक संजय सिंह गुट में शामिल हो गये।

इसी दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपने साथ पटा लिया। इंका के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शुरू से ही वीर बहादुर के खिलाफ थे। गोरखपुर में वीर बहादुर के विरोधी रामपाल सिंह, इंका के प्रादेशिक महामंत्री तथा संजय सिंह गुट के खास आदमी बन गये। इसीलिए आरोप लगाया जाता है कि सदस्यता अभियान के दौरान संजय सिंह के इशारे पर बड़ी संख्या में इंका के फर्जी सदस्य जिले-जिले में बनाये गये।

वीर बहादुर ने कई बार दिल्ली दरबार में शिकायत की कि महावीर प्रसाद को हटाकर बलराम सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाये, लेकिन प्रधानमंत्री-निवास में संजय सिंह की घुसपैठ के कारण वीर बहादुर इस मुहिम में सफल नहीं हो सके।

वीर बहादुर को शिकायत है कि राजा के खिलाफ उनकी लड़ाई में उत्तर प्रदेश का इंका संगठन साथ नहीं दे रहा है। प्रदेश में सूखे की विकट समस्या है, लेकिन प्रदेश इंका इस समस्या के समाधान में भी सरकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है।

ठीक यही स्थिति प्रदेश में युवा कांग्रेस की है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह भीतर-भीतर राजा को समर्थन दे रहे हैं। उनके जिले आजमगढ़ के दोनों प्रमुख नेता रामधन और राजकुमार राय राजा के साथ हो गये हैं। अभी तक ये दोनों नेता जिले की राजनीति में संतोष सिंह को समर्थन देते थे, जबकि उनके कट्टर विरोधी आजमगढ़ के कल्पनाथ राय इन दिनों दिल्ली दरबार के खास बने हुए हैं। अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह देख संतोष सिंह शान्त बैठे हुए हैं।

अधिकांश इंकाइयों की मांग है कि प्रदेश इंका का पुर्नगठन किया जाये और महावीर प्रसाद को हटाकर अब्दुल रहमान खां नश्तर को अध्यक्ष बनाया जाये। इस बारे में वीर बहादुर तर्क देते हैं, "भले ही तमाम लोग राजा के साथ हो जायें, लेकिन नश्तर उनके साथ नहीं जा सकते हैं। क्योंकि राजा ने एक समय में नश्तर को मंत्री-पद से हटाकर अपमानित किया था।"

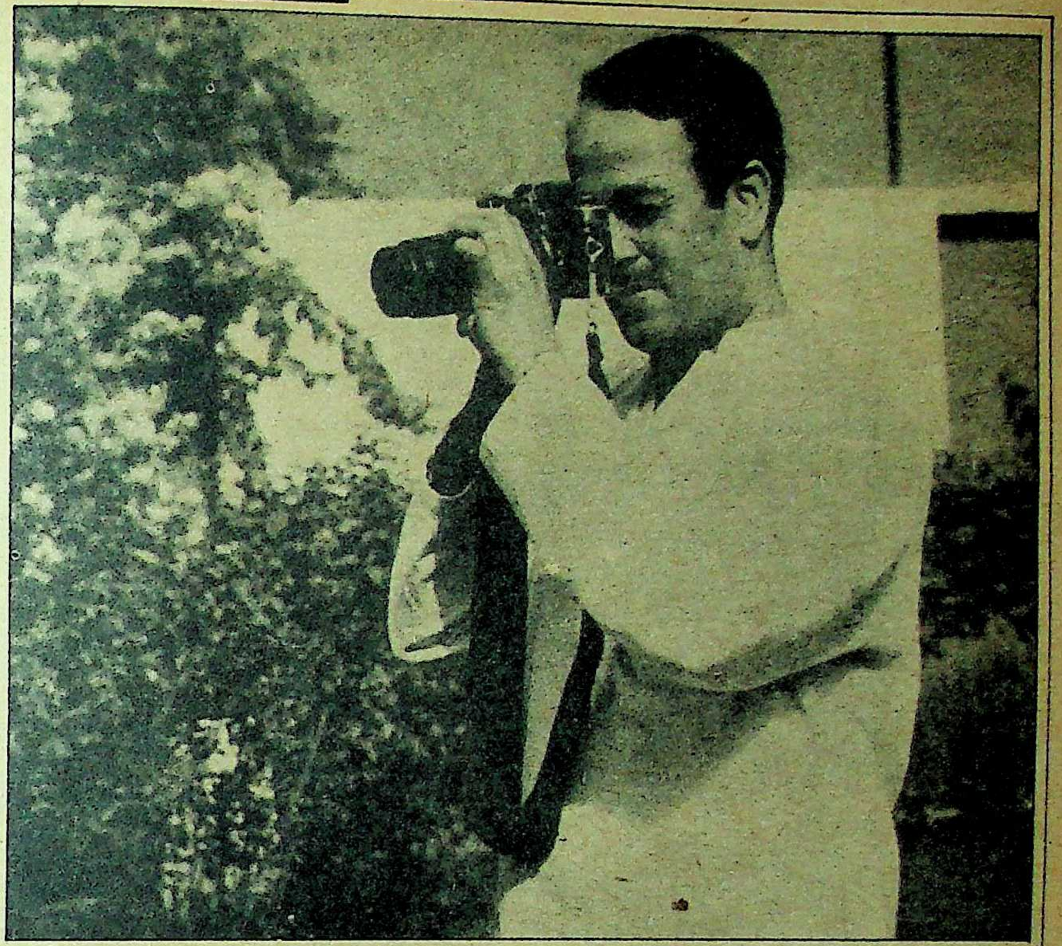

मेरा निशाना राजीव हैं: संजय सिंह

उत्तर प्रदेश में ३ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाये जाने के बाद संजय सिंह को लगा कि कहीं वीर बहादुर सिंह उन्हें हटाने की कार्यवाही न शुरू कर दें, इसी बचाव के तहत संजय सिंह ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। संजय सिंह इस बारे में बताते हैं, "वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश में राजा के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी करेगा, जिसका अपना दामन पाक-साफ नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से वीर बहादुर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गोरखपुर की रामगढ़ ताल परियोजना तो उनके भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है। कलकत्ता में उन्होंने एक बड़ा व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनवाया है। गोरखपुर में अपनी पत्नी के नाम एक आलीशान मकान खरीदने की प्रक्रिया हो रही है। मैं सारे प्रमाण इकट्ठा कर रहा हूं।"

लेकिन अभी यह युद्ध चल ही रहा था कि संजय सिंह ने अपनी रणनीति बदलकर सीधे राजीव गांधी से लोहा लेना शुरू कर दिया। मात्र ३४ वर्ष की अवस्था में संजय सिंह ने बगावत करके अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाया है। १९८४ में राजीव गांधी अमेठी से ३ लाख ६५ हजार ४१ मतों से विजयी हुए थे, जिनमें लगभग आधे मत अकेले अमेठी विधानसभायी क्षेत्र के थे। देखना है अब राजीव गांधी का साथ छोड़ देने से अमेठी की जनता क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। आगामी चुनाव संजय सिंह के भविष्य का नियंता होगा। यदि उन्होंने अपने जनाधार को बरकरार रखते हुए राजीव गांधी को हरवा दिया, तो वह राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे, अन्यथा वह भी कांग्रेस छोड़कर गये अन्य नेताओं की तरह विस्मृति के अंधेरे में खो जायेंगे।

लेकिन संजय सिंह के इस्तीफा देने के बाद उनके अमेठी पहुंचने पर जो स्थिति बनी है, उससे लगता है कि संजय सिंह ने राजीव गांधी की जड़ें उखाड़ने का अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान को कांग्रेसी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। २३ अगस्त को जब संजय सिंह अमेठी पहुंचे, तो उनका एक नायक की तरह स्वागत हुआ और शहर तथा ब्लाक स्तर के सभी कांग्रेसी नेताओं ने राजीव गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए पार्टी से इस्तीफे दे दिये। इन नेताओं ने कहा कि अब आगे से किसी भी बाहरी व्यक्ति को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा। संजय सिंह का कांग्रेसियों ने ही नहीं, संजय विचार मंच के लोगों ने भी स्वागत किया है। जाहिर है कि संजय सिंह प्रतिशोध की मुद्रा में हैं और उनके प्रभाव तथा उनकी संजय गांधी मार्का आक्रामक राजनीति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अमेठी संसदीय क्षेत्र को राजीव गांधी के लिए निष्कंटक रहने देंगे।

—अजय कुमार

रोशनी विकास की, संकल्प एकता का

विगत चालीस वर्षों में देश के सामने अनेक बार विकराल समस्याएं आयीं। ऐसी ताकतों ने सिर उठाया जिनसे विलगाव को, बिखराव को और टूटन को बल मिला। लेकिन हर बार राष्ट्रीय एकता की जड़ें बहुत मजबूत सिद्ध हुई। अस्थिरता फैलाने के निहित स्वार्थों के मंसूबे नाकामयाब हुए। आज का दिन देश की इस एकता को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेने का दिन है। देश की एकता ने ही हमें प्रगति की राह पर, आत्म निर्भरता की मंजिल की ओर चलने की प्रेरणा दी, शक्ति दी। एकजुट होकर साधारण-से-साधारण व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए किये गये प्रयास बड़ी सीमा तक सफल रहे।

○ हर बीते वर्ष ने एक नयी आशा को जन्म दिया, एक नये उल्लास-पूर्ण वातावरण की सृष्टि की।

○ उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष की अवधि में सूखा और बाढ़ के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन वर्ष १९८५—८६ के कीर्तिमान उत्पादन ३१३.९५ लाख मी० टन से भी बढ़कर १९८६-८७ में ३१६.६७ लाख मी० टन हो गया। और अब चालू वर्ष में इसे और बढ़ाकर ३४५.२० लाख मी० टन करने का लक्ष्य है।

○ पिछले वित्तीय वर्ष में (१९८६-८७) बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मदों में प्रदेश ने शत-प्रतिशत या इससे भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

○ गरीबों और निराश्रितों के लिए प्रदेश शासन ने विशेष प्रयास किये। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत तीन लाख पचास हज़ार के लक्ष्य की तुलना में तीन लाख अस्सी हजार अनुसूचित परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की।

○ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक आयोग कार्यरत। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राज्य स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक समितियां सक्रिय। उर्दू विकास के लिए राज्यभर में २१४२ उर्दू माध्यम के स्कूल संचालित। सांप्रदायिक उन्माद के फलस्वरूप कष्ट में पड़े लोगों को विगत वर्ष २७ लाख रुपए की सहायता।

○ गांवों में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा शीघ्र समृद्धि लाने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा। चालू सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में ही ३५ हजार से अधिक लघु इकाइयां स्थापित। और अब वर्ष १९८७-८८ में २० हजार और इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य। बड़े और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए वर्ष १९८६-८७ में लगभग ९८ करोड़ रुपयों का ऋण वितरण।

विकास की इस निरंतर फैलती बेल को हमारी एकता सिंचित पुष्पित करेगी

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित

दा-दी फोमोलिन का
[illegible] नहीं

कपिल देव

एक मौका और

रिलायंस कप के लिए भारतीय टीम की कप्तानी फिर से कपिल देव को सौंपकर चयनकर्ताओं ने सारी अटकलों पर रोक लगा दी है। कप्तानी के दूसरे दावेदार वेंगसरकर को उपकप्तान बनाया गया है। लेकिन कपिल और वेंगसरकर आपसी मतभेदों को भुलाकर क्या दोबारा विश्वकप भारत की झोली में डाल पायेंगे ? जहां रिलायंस कप में कपिल देव की कप्तान के रूप में अंतिम परीक्षा होगी, वहीं वेंगसरकर के भावी कप्तान बनने की योग्यता की परख भी हो जायेगी। कपिल और वेंगसरकर के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम कैसी होगी ?

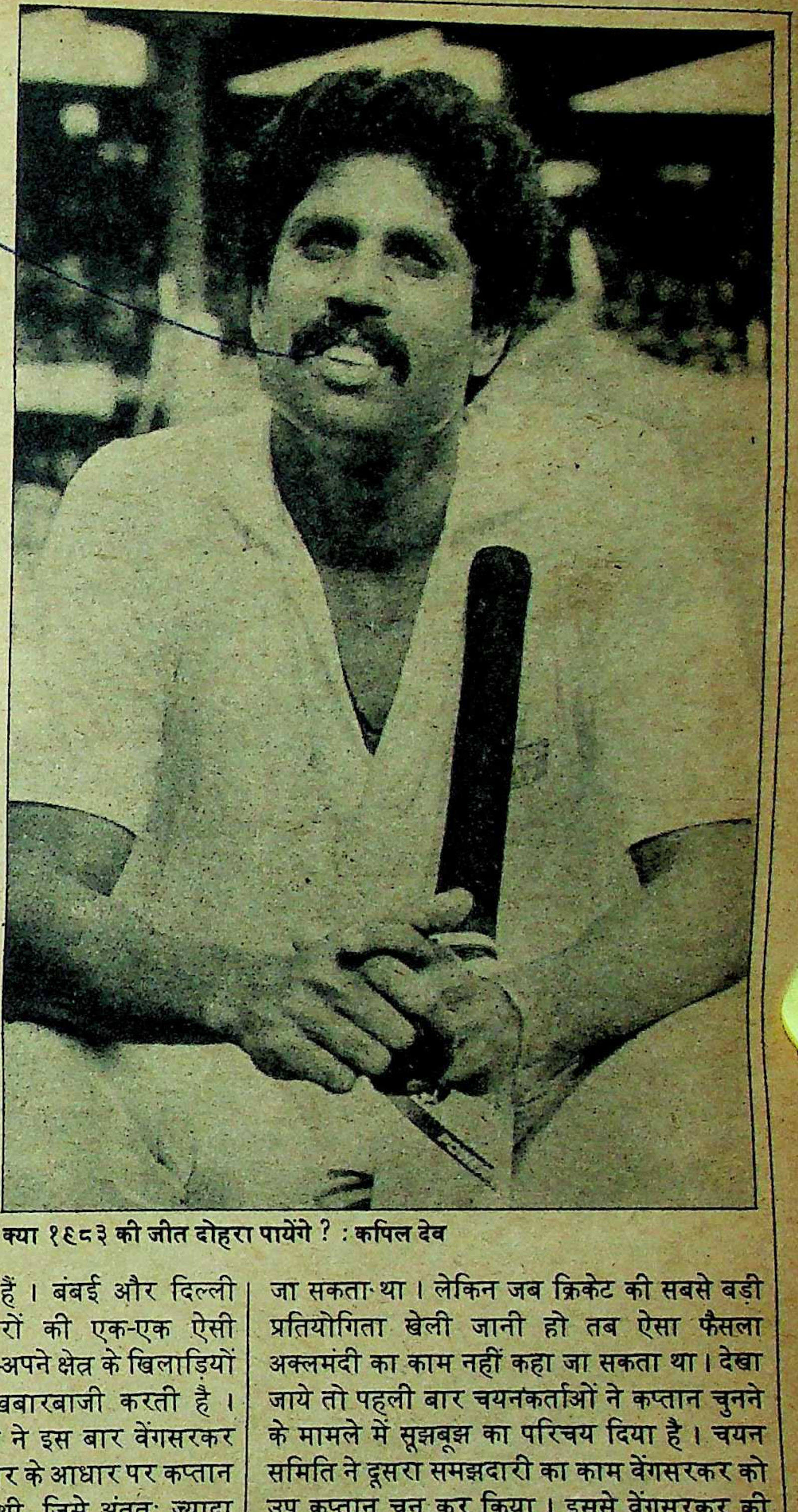

क्या १९८३ की जीत दोहरा पायेंगे ? : कपिल देव

कप्तान और टीम के खिलाड़ियों का चयन निश्चित रूप से काफी सिरदर्द और चुनौती भरा काम होता है। सही और गलत चयन पर टीम का प्रदर्शन निर्भर करता है। चयन प्रक्रिया के बाद चयनकर्ता मुंह बाये नतीजों का इंतजार करते रहते हैं। यदि टीम का प्रदर्शन ठीक रहा, तो वे चैन की सांस लेते हैं और यदि न रहा तो गुस्सा भी उन्हीं को झेलना पड़ता है। मगर इस बार कप्तान के चुनाव में चयनकर्ताओं के सामने कोई दिक्कत नहीं थी। वजह साफ है कपिल के अलावा कोई प्रमुख दावेदार था ही नहीं। गावस्कर ने कप्तान पद की दावेदारी से खुद को पहले ही अलग कर लिया था। रवि शास्त्री का हाल का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और न ही उनके पास इतना अनुभव ही है कि कप्तान बनने के लिए कपिल के सामने खड़े हो सकें। हां, बंबई की पत्र-पत्रिकाओं ने जरूर दिलीप वेंगसरकर का नाम कप्तानी के लिए उछाला था। हालांकि, वेंगसरकर ने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की थी कि वह कप्तान बनना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वह इसके लिए इच्छुक ही नहीं हैं। मगर वह अपनी सीमाएं पहचानते हैं। बंबई और दिल्ली दोनों जगह खेल पत्रकारों की एक-एक ऐसी लॉबी है जो हर बार अपने-अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को उचकाने के लिए अखबारबाजी करती है। इसी के चलते बंबई लॉबी ने इस बार वेंगसरकर को उनके लंबे क्रिकेट कैरियर के आधार पर कप्तान बनाने की सिफारिश की थी, जिसे अंततः ज्यादा तरजीह नहीं दी गयी। यदि क्रिकेट प्रेमियों का नजरिया लिया जाता, तो उनका भी इरादा कपिल को ही कप्तान बनाने का था। नवभारत टाइम्स ने कुछ दिनों पहले पाठकों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें सबसे ज्यादा मत कपिल देव को (१३,२७३) उसके बाद क्रमशः वेंगसरकर (८,१७२), गावस्कर (५,४२८) और शास्त्री (२,६३९) को मिले थे।

गावस्कर द्वारा कप्तान पद के लिए कपिल को ही उपयुक्त बताये जाने का चाहे जिसने जो मतलब लगाया हो, मगर इसमें दो मत नहीं होना चाहिए कि उनका कहना सौ फीसदी ठीक था। यदि कोई टेस्ट श्रृंखला होनी होती, तो आजमाइश के तौर पर किसी दूसरे खिलाडी को कप्तान चुना जा सकता था। लेकिन जब क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेली जानी हो तब ऐसा फैसला अक्लमंदी का काम नहीं कहा जा सकता था। देखा जाये तो पहली बार चयनकर्ताओं ने कप्तान चुनने के मामले में सूझबूझ का परिचय दिया है। चयन समिति ने दूसरा समझदारी का काम वेंगसरकर को उप कप्तान चुन कर किया। इससे वेंगसरकर की भविष्य के कप्तान के रूप में परख भी हो जायेगी।

हमारे यहां परंपरा रही है कि कोई भी कप्तान एक-दो टेस्ट श्रृंखलाएं क्या हार जाये, उसको हटाने की चर्चा जोरों से चल पड़ती है। ऐसे में उसके पूर्व प्रदर्शन और अनुभव को ताक पर रख दिया जाता है। यह विडंबना ज्यादातर कप्तानों को झेलनी पड़ी है, चाहे वह वाडेकर रहे हों या बेदी। अब यही कपिल देव हैं जिन्होंने एक-एक करके ढेर सारी उपलब्धियां (प्रूडेंशियल कप, बेंसन एंड हेजेज कप, शरजाह कप) भारत की झोली में डाल दी थीं। मगर हाल ही में भारत पाकिस्तान के हाथों क्या हार गया, उन्हें हटाने की मांग की जाने लगी। टीम या खिलाड़ी का प्रदर्शन कभी एक सा नहीं रहता। हार-जीत का

ग्राफ ऊपर-नीचे होता रहता है। इसलिए एक बार की असफलता को देखकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं होता।

माना कि वेंगसरकर एक लंबे अरसे से भारतीय टीम के अभिन्न अंग बने हुए हैं। उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी असाधारण रहा है। वह टीम के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। मगर कप्तान बनने की क्या बस यही कसौटियां हैं। कप्तानी का अनुभव भी कुछ मायने रखता है या नहीं ? वेंगसरकर के पास कप्तानी का जरा भी अनुभव नहीं है। इस मामले में भूतपूर्व खिलाड़ी नारी कांट्रेक्टर का कहना बिलकुल ठीक है कि "वेंगसरकर के पास टाटा की कप्तानी के अलावा और है क्या ?" ऐसी स्थिति में जब विश्व विजेता का खिताब बचाये रखना ही मुश्किल लग रहा हो किसी ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना बेवकूफी पूर्ण निर्णय माना जाता जिसने विश्वस्तर के किसी मैच में कप्तानी का उत्तरदायित्व पहले न उठाया हो। जहां तक कपिल का सवाल है, वह लगभग पांच साल से भारतीय टीम का नेतृत्व संभाले हुए हैं। इस लिहाज से उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। वह इमरान के समान चतुर कप्तान भले ही साबित न हुए हों मगर उनकी उपलब्धियां बताती हैं कि उनमें टीम को एकजुट रखने की कला है। धीरे-धीरे वह कप्तानी के अन्य गुरों से भी वाकिफ हो गये हैं। इमरान की तरह हार के समय भी संतुलन बनाये रखकर पराजय को जीत में बदलने की कला कपिल में आ जाये तो विश्व स्तर का यह आलराउंडर विश्व स्तर का कप्तान भी साबित हो सकता है।

कपिल को कप्तानी न सौंपे जाने से टीम में फूट पड़ने की भी संभावनाएं थीं। जहां तक कपिल का सवाल है, वह पहले ही कह चुके थे कि, "मैं वेंगसरकर की कप्तानी में नहीं खेलूंगा।" उनका यह बयान निश्चित ही घमंड भरा और हठीला है। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है कि यदि वेंगसरकर को कप्तान बनाया जाता तब क्या होता ? टीम एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के सहयोग से क्या वंचित नहीं हो जाती ? वह खिलाड़ी जिसने पिछले विश्व कप की जीत में मुख्य भूमिका निभायी थी और जो निर्विवाद रूप से अब भी टीम का कर्णधार है, न खेलता तो टीम कमजोर नहीं होती ? संभव है कपिल को समझा-बुझाकर खेलने को राजी भी कर लिया जाता। मगर एक दरार जो पैदा हो जाती वह मैदान में भी साफ दिखलायी पड़ती। विश्व कप जीतने के लिए खेलने वाली टीम खेमों में बंटी नजर आती। हां खेल भावना के लिहाज से कपिल का वेंगसरकर की कप्तानी में न खेलने की बात कहना कपिल जैसे खिलाड़ी के लिए ठीक नहीं है। कप्तान कोई हो, खेल खेल की तरह होना चाहिए। कहीं ऐसा हो जाता कि वेंगसरकर कप्तान चुन लिये जाते और कपिल उनकी कप्तानी में न खेलते तो कपिल, गावस्कर की तरह ही विवादास्पद हो जाते और उन्हें भी खेल प्रेमियों के रोष का सामना वैसे ही करना पड़ता जैसे गावस्कर को कलकत्ता में न खेलने पर करना पड़ा था।

निश्चय ही अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए कपिल को यह आखिरी मौका दिया गया है। यह विश्वकप उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। उनका और उनकी टीम का प्रदर्शन ही कप्तानी का भविष्य भी निर्धारित करेगा।

टीम का चयन कप्तान के चुनाव में चयनकर्ताओं ने जितनी दूरदर्शिता दिखायी, ठीक उसका उलटा उन्होंने टीम के चुनाव में किया। प्रशिक्षण के लिए चौबीस सदस्यीय टीम में ज्यादातर नये खिलाड़ी लिये गये हैं। नये खिलाड़ियों के चयन पर किसी को कोई एतराज नहीं होता। बल्कि यह तो अच्छा है कि ज्यादा-से-ज्यादा नया खून टीम में शामिल होता रहे। मगर इसके लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं था। सवाल किया जा सकता है कि क्या इन नये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त समय है या फिर उन्हें सीधे मैदान में उतार दिया जायेगा ? रिलायंस कप के पहले केवल एक प्रशिक्षण शिविर १ सितंबर से २५ सितंबर तक लगाया जायेगा। इन २५ दिनों में नये खिलाड़ियों की क्षमताओं को परखने के क्या मापदंड होंगे, यह समझ के बाहर है ?

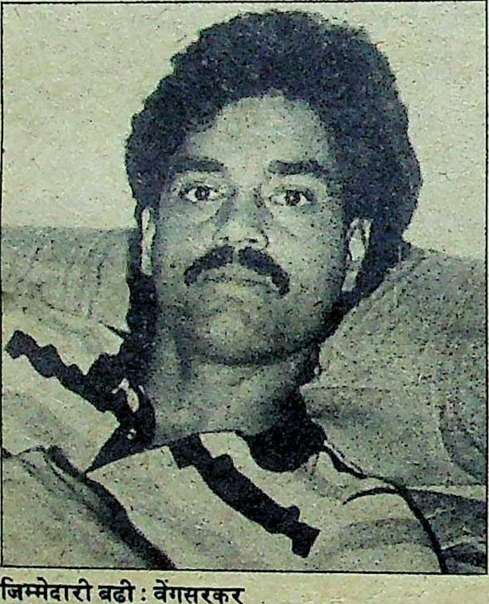
जिम्मेदारी बढ़ी : वेंगसरकर

टीम के चयन में हर बार की तरह इस बार काफी देर लगायी गयी। कपिल देव ने इसके लिए चयन समिति को आड़े हाथों भी लिया। उनका कहना था कि चार देशों ने जहां अपनी १४ सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है वहां मेजबान देश की चयन समिति २५ खिलाड़ियों का चुनाव भी नहीं कर पायी। विडंबना देखिये, यह बात टीम चुने जाने के डेढ़ महीने पहले कही गयी थी। इस तरह टीम का चयन कम-से-कम तीन महीने देर से हुआ। इस लेट-लतीफी की वजह से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पायेगा और न ही वे खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पायेंगे। खास तौर पर नये खिलाड़ियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतने कम समय में टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ ठीक-ठीक तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा, जो कि क्रिकेट का सबसे जरूरी पक्ष है।

नयी टीम में सबसे ज्यादा खलनेवाली बात है रमण लांबा का चयन न होना। हालांकि प्रारंभिक उपलब्धियों के बाद लांबा अपना प्रदर्शन कायम नहीं रख सके थे, मगर धीरे-धीरे वह अपने को विश्व क्रिकेट के अनुसार ढालते जा रहे थे। खास तौर पर एक दिवसीय क्रिकेट में तो वह लायक बल्लेबाज सिद्ध हो सकते थे। बजाय बिलकुल नये खिलाड़ी को खिलाने के लांबा के तजुर्बे का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद होता। मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ का निकाला जाना कोई ज्यादा चौंकानेवाला नहीं रहा। पिछले विश्वकप में मदन लाल जरूर भरोसे के गेंदबाज सिद्ध हुए थे, मगर भारतीय परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते इसमें संदेह है। मोहिंदर पिछले विश्व कप में 'मैन आफ द सिरीज' जरूर रहे, मगर उनका प्रदर्शन उसके बाद कभी अच्छा नहीं रहा।

मौजूदा टीम में नये खिलाड़ियों की भरमार होने के बावजूद किसी नये खिलाड़ी को खिलाये जाने की उम्मीद बहुत कम है। नियमित बल्लेबाजों के अलावा यदि किसी और की जरूरत पड़ी तो अरुण लाल और नवजोत सिंह सिद्धू में से किसी एक को आजमाया जायेगा। इसके अलावा बंबई के संजय मंजरेकर और हैदराबाद के अब्दुल कयूम का प्रदर्शन पिछले सत्र में काफी अच्छा रहा है। यदि मध्यमक्रम में किसी नये बल्लेबाज को लेने की सोची गयी, तो इनमें से किसी की लाटरी खुल सकती है।

पिछली श्रृंखलाओं में स्पिनरों की सफलता को देखकर ही शायद चयनकर्ताओं ने अपना ज्यादा विश्वास स्पिन गेंदबाजों पर जताया है। कम-से-कम नयी टीम में स्पिनरों की संख्या देखकर तो ऐसा ही लगता है। टीम में पांच स्पिनर रवि शास्त्री, मनिंदर सिंह, शिवलाल यादव, गोपाल शर्मा और शिवराम कृष्णन को लिया गया है। भारतीय पिचें स्पिनरों की मददगार साबित हुई हैं। रिलायंस कप के लिए पिचें भी भारतीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही तैयार की गयी होंगी। यदि स्पिनरों के प्रभुत्व की बात सही साबित होती है, तो प्रारंभिक आक्रमण भी कपिल, बिन्नी और चेतन के इर्द-गिर्द केंद्रित रहेगा। किसी फेरबदल की जरूरत महसूस भी हुई, तो किसी नये खिलाड़ी को मौका देने के बजाय मनोज प्रभाकर या राजू कुलकर्णी को लिया जायेगा।

इस सबके बावजूद एक नये खिलाड़ी का भी पलड़ा भारी नजर आता है और वह है, अजय शर्मा। एक दिवसीय मैचों में हरफन मौला खिलाड़ियों का बहुत महत्व होता है। पिछले सत्र में बल्ले और गेंद दोनों से उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। इस लिहाज से किसी भी नये खिलाड़ी के मुकाबले अजय को मौका मिलने के ज्यादा अवसर हैं।

—मुकेश जैन

ज्ञानीजी अब कैसे हैं?

पता नहीं कोई खास कारण था या नहीं—ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद लगातार दस दिनों तक अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनी, सिवाय उस समय के जब वह प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कोलंबो वापसी पर मिलने गये थे। ज्ञानीजी 'माया' प्रतिनिधि को बता रहे थे, "मैं उन पर हुए हमले की खबर से चिंतित था। वह भारत-श्रीलंका समझौते के विवरणों की जानकारी देते रहे। मैं बिना बोले सब सुनता रहा। अब मैं राष्ट्रपति नहीं हूं।" इसके बाद वह श्रीगुरुग्रंथ साहब के शबद सुनाते हैं, "मन अपने त बुरा मिटाना, सकल संग हमको बनाइया।" —जिस स्थिर-शांत चित्त से वह बोल रहे थे, उससे लगता था कि अब वह संन्यस्त भाव में आ गये हैं। भारतीय राजनीति में बोफोर्स, फेयरफैक्स आदि से आये राजीव विरोधी जिस तूफान के वह केंद्र-बिंदु बन गये थे, वह तूफान यद्यपि अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति भवन छोड़ने के साथ ही उस तूफान से ज्ञानीजी ने किनारा कर लिया है।

यह उनकी राजनीतिक कुशलता ही थी कि उन्होंने स्वयं को भारतीय राजनीति के उस केंद्र-बिंदु तक पहुंचा दिया था जहां उससे पूर्व भारत का कोई राष्ट्रपति नहीं पहुंचा था। पिछले तीन-चार मासों में तो ऐसा समां बंधा था कि राष्ट्रपति भवन छोड़ने के अंतिम क्षणों तक पूरा मुल्क उनकी ओर ही देखता रहा। कुछ दम साधे हुए थे, तो कुछ उल्लसित भाव से किसी चमत्कार की आशा कर रहे थे। अब पूरे मुल्क की निगाहें उन दो लिफाफों पर टिकी रहेंगी, जिन्हें वह इस उम्मीद में सीलबंद कर चुके हैं कि इन्हें सार्वजनिक बनाने के लिए उनके जीवनकाल में उन्हें मजबूर नहीं किया जायेगा। इन लिफाफों के विवरण सबकी उत्सुकता का केंद्र बन गये हैं। संभव है इनसे कुछ ऐसी स्तंभित कर देनेवाली बातें उजागर हों, जिनसे अनेक बड़ी राजनीतिक हस्तियों पर आफत टूट पड़े। लोग यह भी जानने को उत्सुक हैं कि राष्ट्रपति भवन की प्राचीरों में उन क्षणों में वास्तव में क्या हुआ था, जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि राजीव-विरोधी तूफान से किनारा करने के एवज में ज्ञानीजी से पांच करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। कोई नहीं

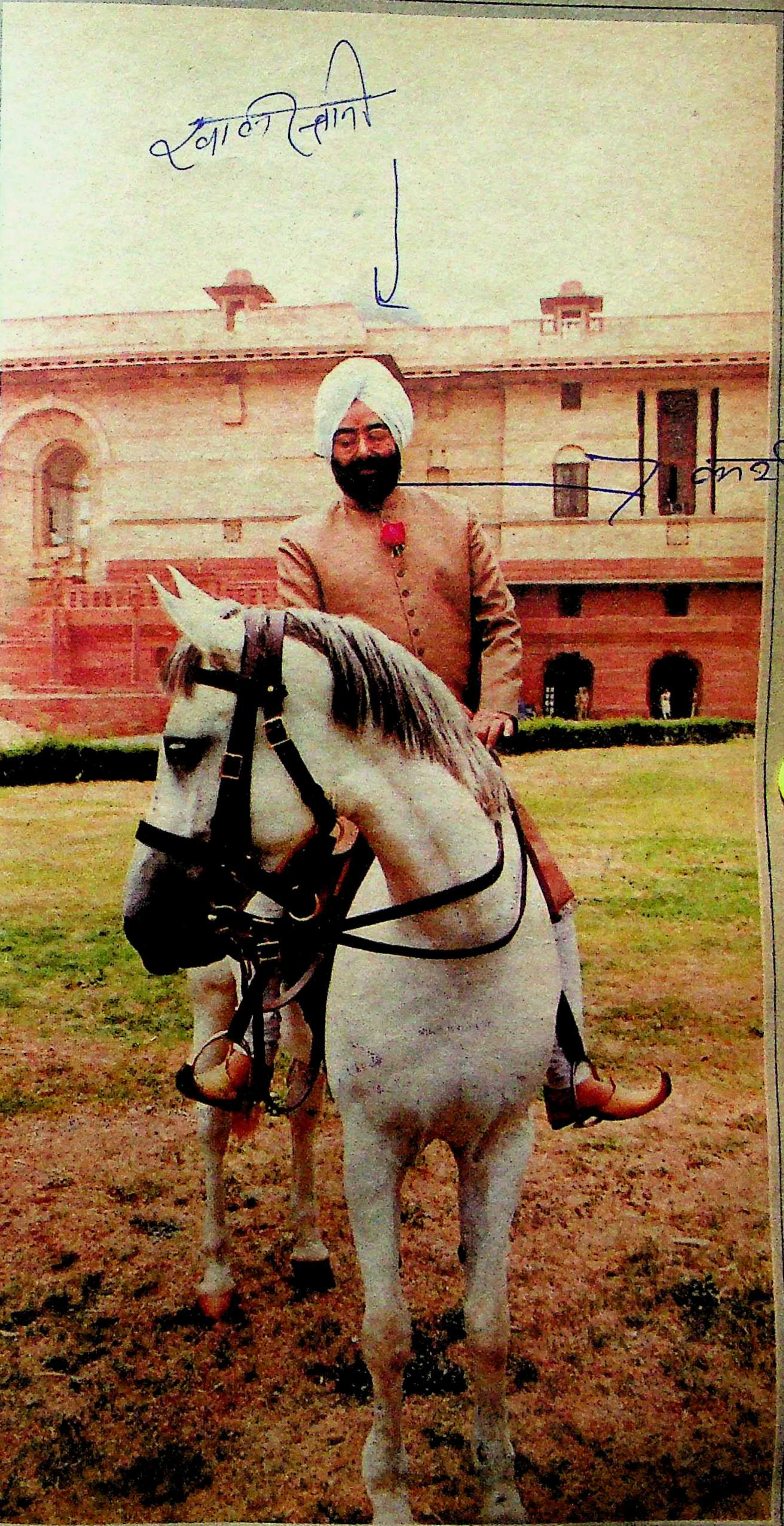
खालिस्तानी

कश्मि

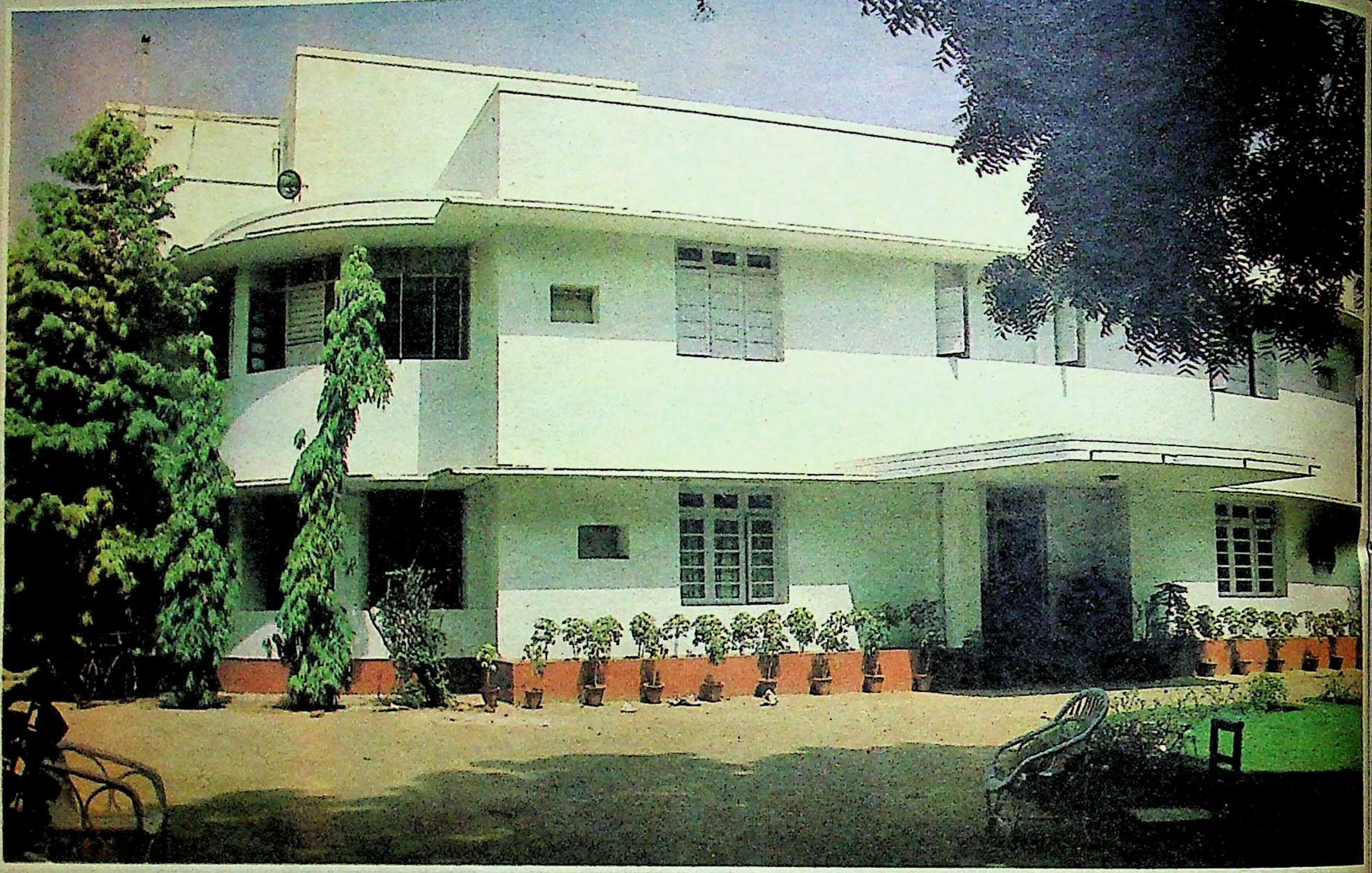

जानता वे लिफाफे कहां हैं? वे न ज्ञानीजी के पास हैं और न ही उनके गृहनगर में। वे अज्ञात स्थान पर सुरक्षित हैं, जहां से वे उपयुक्त समय पर उद्घाटित होंगे। ज्ञानीजी शांत भाव से अर्जुन देवजी का कथन सुनाते हैं, "सोई डर्‌या जो पाप कमाइया...ना कोई बैरी, नाहि बेगाना-सकल संग हमको बनाइया।" तूफान के बाद की निर्मल शांति उनके चेहरे पर वास करने लगी है, जिस पर पश्चाताप की शिकन नहीं है। अब वह अपने अतीत के सुखद क्षणों को ही याद करना चाहते हैं, खासकर उन दिनों को जो उन्होंने श्रीमती गांधी के साथ बिताये थे। बाहरी दुनिया से उनकी विरक्ति इस हद तक है कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति की चालीसवीं वर्षगांठ पर संसद भवन में आयोजित ऐतिहासिक स्मृति समारोह में उपस्थित नहीं थे।

ज्ञानी जैल सिंह का छह कमरों का नया आवास ६, सरकुलर रोड राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास के इतना निकट है कि कार से वहां दो मिनटों में पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन से यहां आने के बाद उनकी सारी दुनिया भले ही बदल गयी हो, लेकिन वे बातें बिलकुल नहीं बदली हैं, जो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते समय उनके साथ थीं। बढ़ी उम्र के बावजूद उनकी जिंदादिली ज्यों-क़ी-त्यों है। अब भी वह नियम से प्रातः ५ बजे उठ जाते हैं। यहां मुगल गार्डन्न की मखमली घास नहीं है, फूलों से महकती हवा के झोंके भी नहीं हैं—खाली जगह के नाम पर या तो एक बरांडा है या पिछवाड़े एक छोटा लान है, जिस़में आनेवाली सर्दियों में शायद कुछ फूल खिलें। फिलहाल ज्ञानीजी अपना भ्रमण-योगासन आदि अपने शयन कक्ष में ही कर लेते हैं और दोपहर का भोजन वही दोपहर सवा एक या डेढ़ बजे और रात्रि भोजन साढ़े नौ बजे। अब वह अकसर अकेले भोजन करते हैं और संभवतः अब उन्हें अकेले ही रहना है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों को साथ रख पाना आर्थिक दृष्टि से उनके लिए संभव नहीं रह गया है। अभी उनका एक पौत्र उनके साथ है, लेकिन वह भी यहां तब तक है जब तक कि करीब सौ बंडलों में बंधी उनकी पुस्तकें तरतीब से नहीं लग जातीं। ज्ञानीजी का शयनकक्ष प्रथम तल पर ठीक उनके पूजागृह के सामने है; जहां सोने की कसीदाकारी से चमकते कपड़े में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, साथ ही गुरुमुखी में लिखी अनेक धर्मों की पुस्तकें भी हैं। भोजन कक्ष की गर्मी बर्दाश्त क़े बाहर है। उनकी बैठक का कमरा राष्ट्रपति भवन के उस कमरे से भी छोटा है, जहां कभी उनका सहांयक (एडीसी)

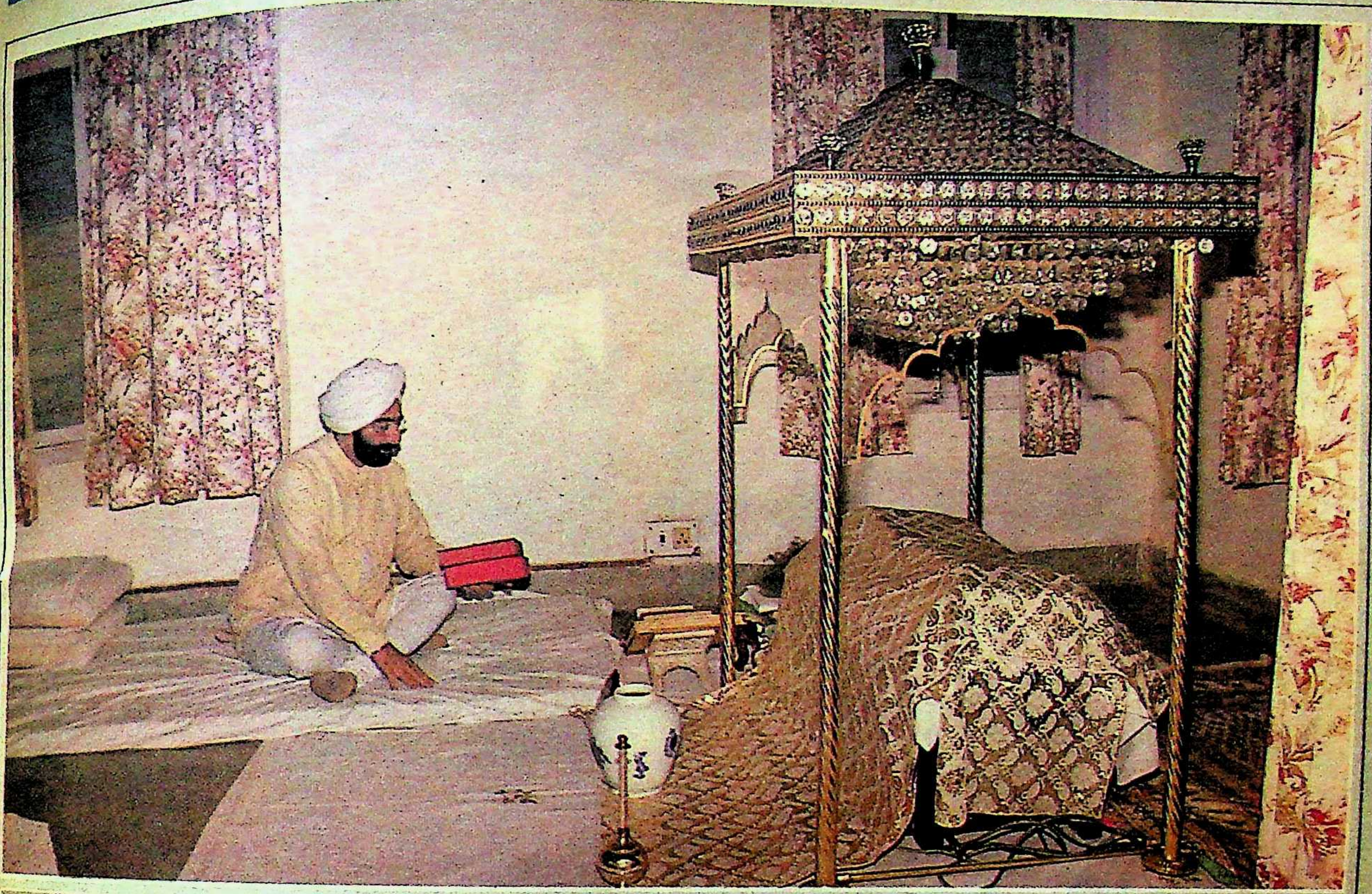

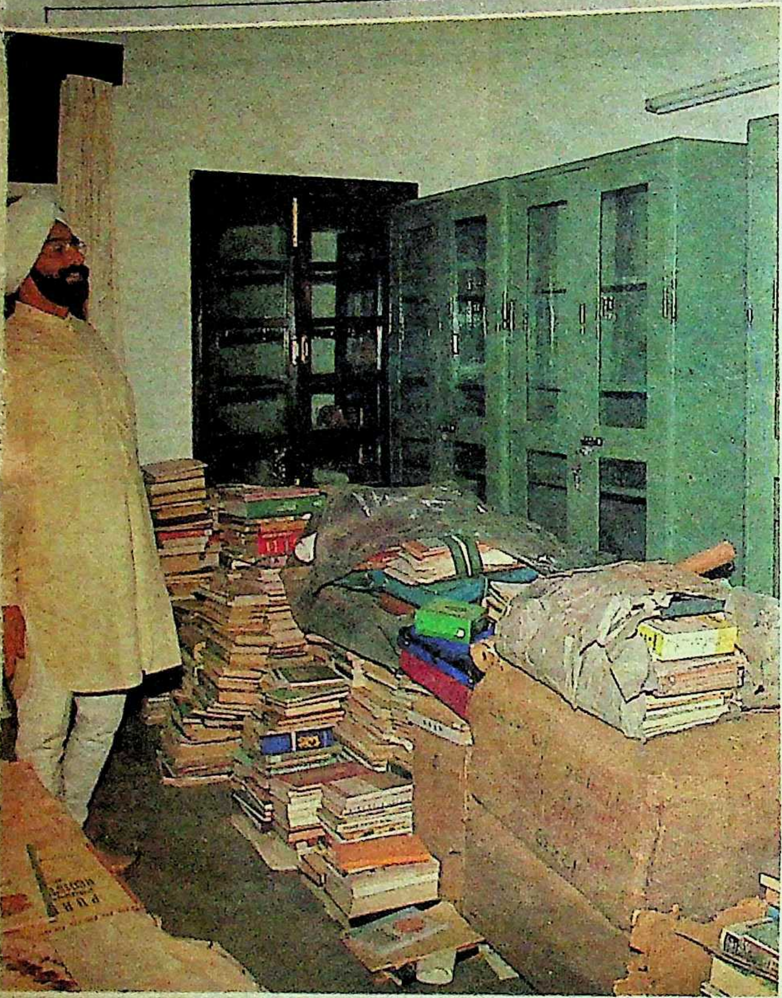

अतिथियों का स्वागत किया करता था। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए यहां सिर्फ एक एयर कंडीशनर लगा है। राष्ट्रपति भवन के शताधिक वातानुकूलित कमरे, असंख्य सेवक, छह दरवाजों की लिमोजिन कार, अब यहां नहीं है। राष्ट्रपति भवन में बिताये दिनों को ज्ञानीजी एक सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं। लेकिन वहां तैनात छह सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, संतरी से रक्षित दरवाजे, दस फुटी ऊंची चहारदीवारी और बरामदे में लगी शक्तिशाली सर्चलाइट का प्रकाश ही बीते दिनों की याद दिलाने के लिए वहां मौजूद हैं जो यह भी संकेत करते रहते हैं कि ज्ञानीजी के प्राणों पर संकट अब भी मौजूद है।

मेहमानों को चाय अब साधारण टी सेट में दी जाती है। चाय की व्यवस्था उनका नया सेवक गढ़वाल का सत्येंद्र सिंह करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर-निवासी सालिगराम भारद्वाज उनके सचिव, टाइपिस्ट, स्वागतकर्ता सब कुछ हैं। वह २० सालों से ज्ञानीजी की सेवा में हैं। इसी प्रकार गढ़वाल का ही ऋषिराम उनका रसोइया है जो उनके गृहमंत्री बनने से लेकर आजतक उनके साथ है।

ज्ञानी जैल सिंह का अभ्युदय अद्भुत था— जिनका अध्ययन सिर्फ 'रेल में या जेल में' हुआ हो, वह न केवल डा० राजेंद्र प्रसाद, डा० राधाकृष्णन, डा० जाकिर हुसैन प्रभृति मनीषियों के समकक्ष पद तक पहुंचे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को नये आयाम भी दिये। पचास वर्ष के कर्मठ सार्वजनिक जीवन से विदा लेने के बाद वह बहुत एकाकी हो जायेंगे, लेकिन अपने कार्यकाल के अंतिम मासों में उन्होंने विपक्षी नेताओं और असंतुष्ट कांग्रेस-इ नेताओं को जिस गंभीरता से तरजीह दी है, उससे यह भी आभास होता है कि यदि परिस्थितियों ने मजबूर किया, तो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास के बीच में स्थित भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का यह साधारण-शांत-एकांत निवास स्थान उनके भूतपूर्व आवास राष्ट्रपति भवन के समान फिर से सरगर्म हो सकता है। ज्ञानीजी के मित्र और स्थापित पत्रकार प्रेम भाटिया ने उनके आवासीय स्थान को देखकर मजाक में कहा था कि ज्ञानीजी ने 'बिस्तर बिछा दिया है, तेरे घर के सामने।' लेकिन इस कथन में यह सचाई भी है कि इस आवास में उनकी उपस्थिति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को उनके कर्तव्यों का बोध कराती रहेगी।

छाया : सुनील सक्सेना

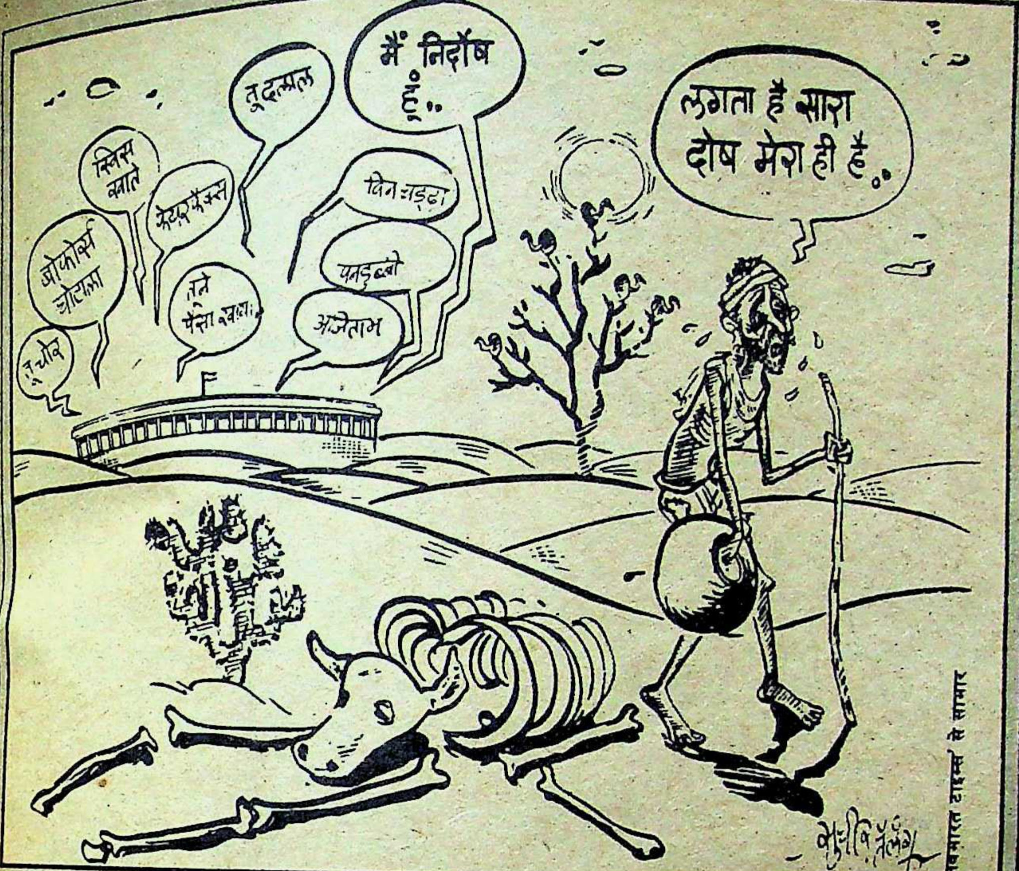
तू चोर
बोफोर्स घोटाला
स्विस खाते
फेयरफैक्स
तूने पैसा खाया
तू दल्लाल
मैं निर्दोष हूं..
विन चड्ढा
पनडुब्बी
अजिताभ
लगता है सारा दोष मेरा ही है..

'नवभारत टाइम्स' से साभार

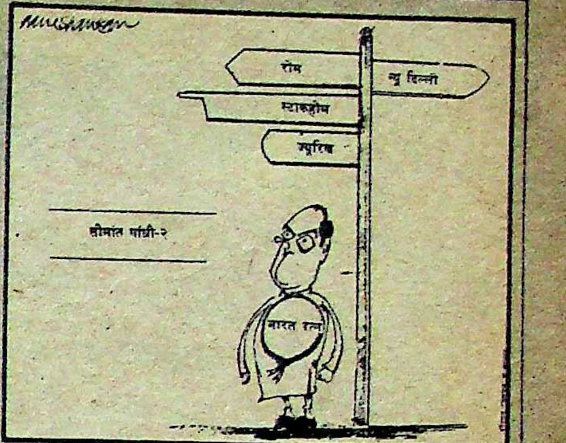
रोम
न्यू दिल्ली
स्टाकहोम
ज्यूरिख
श्रीमंत गांधी-२
भारत रत्न

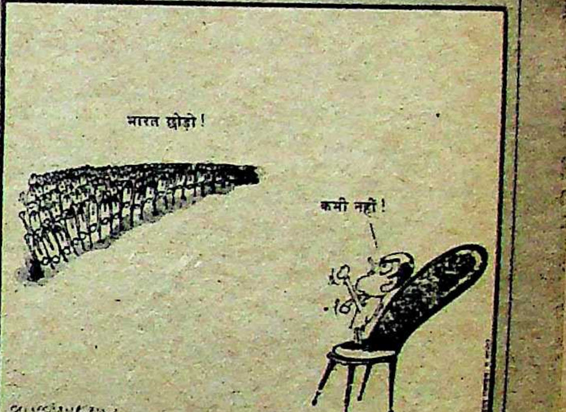

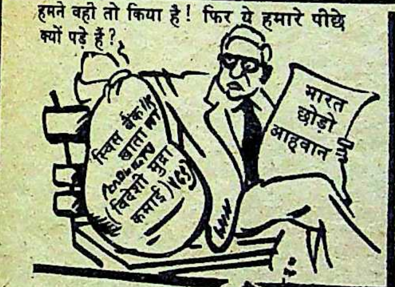
हमने वही तो किया है ! फिर ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं ?
स्विस बैंक में खाता या विदेशी मुद्रा कमाई
भारत छोड़ो आह्वान

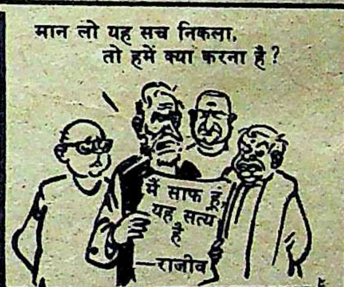
मान लो यह सच निकला, तो हमें क्या करना है ?
मैं साफ हूं, यह सत्य है —राजीव

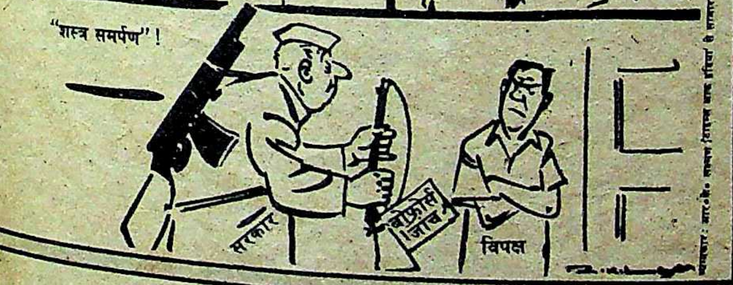
"शस्त्र समर्पण" !
सरकार
बोफ़ोर्स जांच
विपक्ष

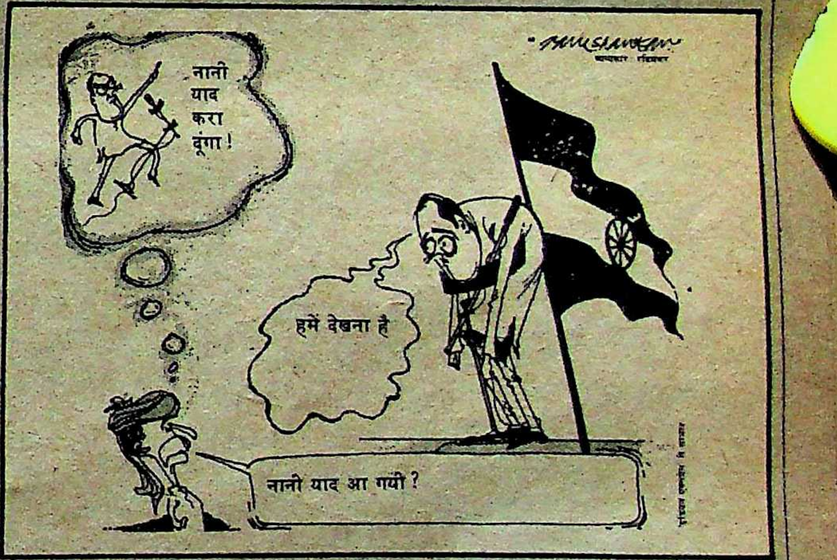
नानी याद करा दूंगा !
हमें देखना है
नानी याद आ गयी ?

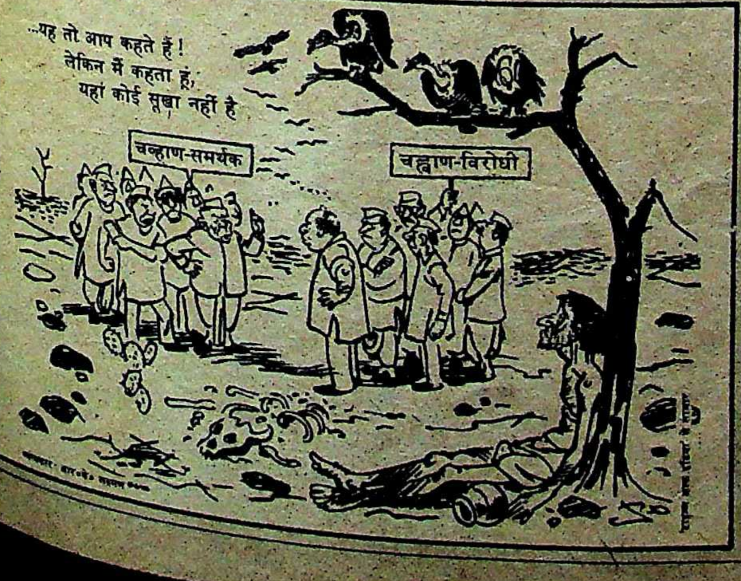
...यह तो आप कहते हैं ! लेकिन मैं कहता हूं, यहां कोई सूखा नहीं है
चव्हाण-समर्थक
चव्हाण-विरोधी

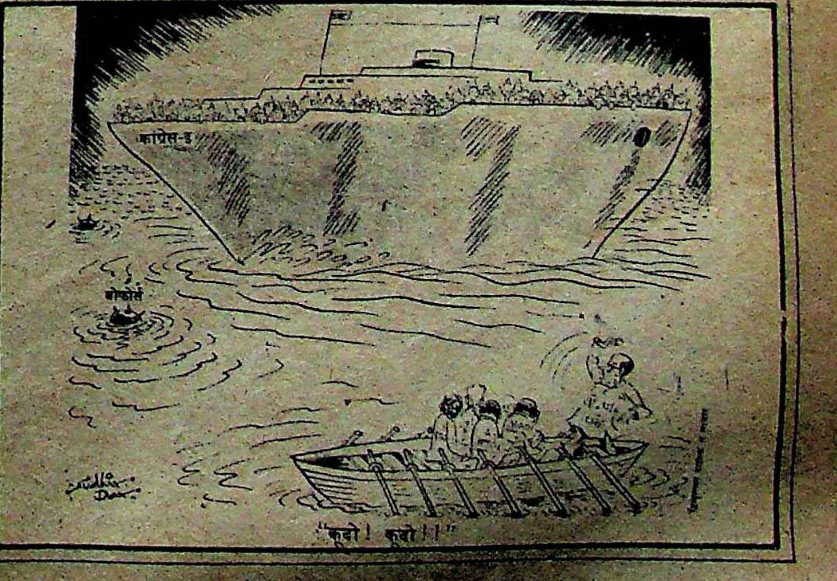

"कूदो ! कूदो ! !"

शेयर बाजार कब तक वीरान रहेगा ?

शेयर बाजार देश के आर्थिक हालात का आइना होता है और यह आइना बतला रहा है कि पिछले दो वर्षों में भारत के औद्योगिक जगत के उत्पादन और मुनाफे में चौंकानेवाली गिरावट आयी है। टेल्को के १०० रुपए के शेयर के १९८६ में भाव ९१० रुपए थे जो अगस्त, १९८७ तक गिरते-गिरते ४३५ रुपए रह गये। यही हाल कमोबेश प्रायः हर उद्योग का है। मध्यम व निम्न आय वर्ग के लाखों शेयरधारकों को लाखों रुपए का चूना लगाकर शेयर बाजार वीरान हो चुका है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए और भारी घाटे से बचने के लिए शेयरधारक अब क्या करें ?

पिछले दो वर्षों से शेयर बाजार अभूतपूर्व मंदी के दौर से गुजर रहा है। शेयरों के भाव एक बार गिरने शुरू हुए, तो फिर उसने थमने का नाम नहीं लिया। लाखों लोगों की जमापूंजी को लीलकर वह वीरान हो चुका है। गत वर्ष १९८६ में ही प्रायः सभी कंपनियों के शेयरों के भाव ४० से ५० प्रतिशत तक कम हुए। इसका मतलब है कि यदि आपने गत वर्ष की सर्वाधिक कीमतों में सौ रुपए के शेयर खरीदे और उन्हें उस वर्ष की सबसे कम कीमत पर बेचा, तो आपको अपनी जेब के ४० से ५० रुपए तक से हाथ धोना पड़ा। १९८७ में तो और भी बुरी हालत है। जिन लोगों ने १९८६ में उस वर्ष की सर्वाधिक कीमतों में शेयर खरीदे और उन्हें १९८७ में बेचा, तो वे उन शेयरों को प्रायः गत वर्ष की सबसे कम कीमत से भी कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर थे। (देखिए तालिका-।) शेयर बाजार में अकसर किसी को लाभ होता था, तो किसी को हानि, लेकिन इस वर्ष तो हर शेयरधारक को घाटा उठाना पड़ा है।

किसी भी शहर के मध्यम आय वर्ग के किन्हीं दस लोगों से शेयर बाजार के बारे में सवाल कीजिए, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यक्ति आपको जरूर बता देगा कि उसने गत दो वर्षों में शेयर बाजार में कितना नुकसान उठाया। कोई नहीं जानता कि शेयर बाजार में तेजी कब आयेगी ? लेकिन जो लोग यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि एक-न-एक दिन शेयरों के भाव चढ़ेंगे, अब वे भी निराश हो चले हैं और यह अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि शेयर बाजार के गिरते भाव कहां जाकर रुकेंगे ?

लाइलाज मर्ज : स्वाभाविक रूप से लोग चिंतित हैं। सरकार ने भी शेयर बाजार में हलचल पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाये, मसलन, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं से शेयर बाजार से शेयर खरीदने के लिए कहा गया। शेयर बाजार के बड़े व्यवसायियों के लिए नयी आचार-संहिता बनायी गयी। लेकिन कुछ उपायों ने तो कुछ समय तक असर डाला, शेष का कोई खास असर नहीं पड़ा। असर पड़ने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि देश की गिरती आर्थिक स्थिति और राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ती अनिश्चितता के माहौल में कोई भी कदम बेजान पड़े शेयर बाजार में नयी जान नहीं फूंक सकता।

जब सत्तारूढ़ पार्टी लगातार एक-के बाद-एक चुनाव हारती चली जाये, तो आप किसी व्यवसायी को यह विश्वास कैसे दिला सकते हैं कि आगे सब कुछ ठीक-ठाक होगा। जब हर दिन के अखबार पंजाब के हालात के बद से बदतर होने की खबरें दे रहे हों, तब लोगों से आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे वहां हालात के बेहतर होने की आशा करने लगेंगे। कौन नहीं जानता कि आतंकवादियों के भय से जब बाजारों, सिनेमाघरों रेस्टोरेंटों आदि में वीरानी छा जाती है, तो व्यवसायी ज्यादा माल नहीं बेच पाता। आज वह उतना माल नहीं बेच पा रहा जितना, वह पहले बेचा

तालिका-।

शेयर बाजार की दुर्दशा

इस तालिका से यह अंदाजा हो सकता है कि शेयर बाजार ने शेयरधारकों को किस कदर नुकसान पहुंचाया है। जिन लोगों ने १९८६ में उस वर्ष की सर्वाधिक कीमतों में (बजाज आटो, डी०सी०एम० और कोलगेट को छोड़कर) जिस भी कंपनी के शेयर खरीदे और उन्हें १९८७ (अगस्त) में बेचा, तो उन्हें उन शेयरों की १९८६ की कम-से-कम कीमतों से भी कम कीमत मिली। कुल मिलाकर भाव तो सभी कंपनियों के गिरे, लेकिन यह गिरावट चौंकानेवाली है, जिससे पता चलता है कि शेयर बाजार किस हद तक बेजान हो चुका है :

क्रम	कंपनी	शेयर के	१९८६		१९८७
		मूलभाव	अधिकतम	न्यूनतम	३ अगस्त
१.	हिंद मोटर्स	१०.००	६५.००	३८.००	२२.५०
२.	बजाज टेम्पो	१०.००	१५०.००	९२.५०	८२.५०
३.	अशोक ले लैण्ड	१०.००	४३.५०	२३.२५	३६.००
४.	टेल्को	१००.००	९१०.००	५२५.००	४३५.००
५.	बजाज आटो	१००.००	४८००.००	१९५०.००	४६२५.००
६.	एसीसी	१००.००	३९८.००	१८६.००	१६३.००
७.	कालगेट	१०.०	३८५.००	२००.००	२२२.००
८.	डीसीएम	१०.००	५८.५०	३०.५०	३८.५०
९.	जुआरी एग्रो	१०.००	१२६.००	७२.००	६३.००
१०.	टिस्को	१००.००	१६१०.००	९७२.५०	७५७.५०
११.	एशियन पेंट्स	१०.००	२८०.००	१३०.००	२४०.००
१२.	निरलोन	१०.००	६९.००	२७.५०	९.५०
१३.	रिलायंस	१०.००	३९४.००	२१२.००	१२६.००

करता था। इसका असर यह हुआ है कि कारखानों में उत्पादन कम करना मजबूरी बन गया। पंजाब में हर व्यवसायी का माल पहले से कम बिका है—स्पष्ट है, कंपनियों के लाभ में कमी आयी है। यदि उनका लाभ कम होता है, तो शेयरधारक को आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि उसे अच्छा लाभ मिलेगा?

व्यवसायी के लिए सर्वाधिक अहमियत रखती हैं, सरकार की आर्थिक नीतियां। ये नीतियां निकट भविष्य में क्या स्वरूप लेंगी—इस पर वह बराबर नजर रखता है। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने पर बड़ी उम्मीदें जगायी थीं। वह दोहराते रहे कि निजी पूंजी विनियोग को हर प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं दी जायेंगी, लायसेंस प्रक्रिया सरल की जायेगी, करों में रियायत दी जायेगी और कंपनियों को अपने माल के दाम तय करने में और अधिक आजादी मिलेगी, आदि-आदि। इनमें से बहुत से वायदे वास्तव में पूरे भी किये गये, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति में मजबूती नहीं आयी। हमारे कल-कारखानों को उतना लाभ नहीं हुआ, जितना कि होना चाहिए था। (देखें तालिका-।।)

कंपनियों पर संकट : इन सब बातों के बावजूद शेयर बाजार के हालात इतने न बिगड़ते यदि कुछ बड़ी कंपनियों को अभूतपूर्व संकटों के दौर से न गुजरना पड़ता। मसलन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के शेयरधारकों की संख्या ही २० लाख है, जबकि प्राय: अन्य सभी बड़ी कंपनियों के कुल शेयरधारकों की संख्या ६० लाख है। इसके साथ-साथ यही वह कंपनी है, जिसने भारी संख्या में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को शेयर बाजार की ओर आकृष्ट किया था। जिन लोगों के पास रिलायंस के दस-दस रुपए के एक हजार शेयर थे, उन्हें सात से दस वर्षों के भीतर एक लाख रुपए से अधिक का लाभ हुआ था।

आठ वर्षों तक शेयर बाजार पर राज करने के बाद रिलायंस संकटों से घिरनी शुरू हो गयी। भारत सरकार का इस कंपनी को १९७५ से संरक्षण प्राप्त था, लेकिन केंद्र में सत्ता समीकरणों के बदलने से सरकार ने अपना वरदहस्त रिलायंस के सिर से उठा लिया। रिलायंस पर यही आफत नहीं आयी थी, बल्कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र समूह के मालिक रामनाथ गोयनका भी इस कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गये थे। गोयनका के समाचार पत्र समूह में रिलायंस के काले कारनामे एक-के बाद-एक उजागर होने लगे कि किस प्रकार इस कंपनी ने गैर कानूनी वित्तीय लेन-देन किया, कच्चे माल व भारी मशीनरी की तस्करी की, कर-चोरी की आदि, आदि। रिलायंस के आर्थिक-अपराधों का खुलासा छपने के कारण वित्त मंत्रालय के लिए इस ओर से आंखें मूंद लेना असंभव हो गया। बाद में रिलायंस के दुर्भाग्य से अचानक ऐसे व्यक्ति (विश्वनाथ प्रताप सिह) को वित्तमंत्री बना दिया गया जिसने ऐसी हर कंपनी को संरक्षण देने से इनकार कर दिया जिसके प्रधानमंत्री या उनके मित्रों से करीबी संबंध थे।

इस प्रकार संकटों से घिरे रिलायंस के शेयरधारकों को दिखायी देने लगा कि इस कंपनी की सर्वोच्चता समाप्त हो रही है। शेयरधारकों के चौकन्ना होने के लिए इतना पर्याप्त था। बहुतों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिये। फिर तो शेयर बाजार में आतंक छा गया और इस कंपनी के शेयरों के भाव एकाएक बहुत नीचे चले गये।

कुलमिलाकर भारत की आर्थिक स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। एक-के बाद-एक बड़ी कंपनियां यह महसूस करने लगी हैं कि उनके उत्पादनों की मांग घट रही है। दूसरे शब्दों में भारत के अर्थतंत्र को मांग की कमी का ग्रहण लग गया है। यहां तक कि जिन उद्योगों ने अपने उत्पादनों की बेहद मांग को देखकर अपनी उत्पादन क्षमता का बेहद विस्तार कर लिया था—वे भी जल्दी ही यह अनुभव करने लगे हैं कि अब उनके लिए अपने उत्पादनों की बिक्री बढ़ाना करीब-करीब नामुमकिन हो गया है। दोपहिया वाहन व कंप्यूटर उद्योग का यही हश्र हुआ है। कंप्यूटरों के पुराने स्टाक को निकालने के लिए कंप्यूटर कंपनियों ने इनके दाम काफी कम कर दिये हैं, फिर भी इनकी मांग नहीं बढ़ रही है। अधिकांश दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां अब पहले से कम वाहनों का निर्माण कर रही हैं। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, जो दोपहिया वाहन की गिरती मांग को देखकर इसके निर्माण का लायसेंस होने के बावजूद इसका निर्माण शुरू करने का साहस नहीं कर पा रही हैं।

इस प्रकार देश का आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक है। इसे एक बार नजरअंदाज कर देनेवाला व्यवसायी भी देश के अनिश्चित राजनीतिक हालात को देखकर शेयर बाजार की ओर रुख करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। फेयरफैक्स, बोफोर्स, कांग्रेस-इ को चुनावों में लगातार मिलती पराजय और कांग्रेस-इ पार्टी के भीतर अंतर्कलह को देखते हुए कोई आदमी आज दावे से नहीं कह पा रहा कि राजीव गांधी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? जब तक देश की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती और आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीदें नहीं बंधती तब तक बेजान पड़े शेयरबाजार में नयी जान फूंकना असंभव है।

—अर्थ विज्ञानी

तालिका-।।

उद्योगों के मुनाफे में कमी

इस तालिका में उद्योगों के अनुसार शेयर भावों के एक मास (१७ मई, १९८७ से १७ जून, १९८७) के इंडेक्स नंबरों के रुख का अध्ययन करने से पता चल जाता है कि मई के मध्य से जून के मध्य तक आते-आते चीनी को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के शेयरों के भाव कम हुए हैं। इसका मतलब है कि हर उद्योग के मुनाफे में निरंतर कमी का रुख बना हुआ है और कमी का यही रुख शेयर बाजार की सबसे बड़ी आफत बन गया है।

शेयर भावों में गिरावट का रुख (उद्योग-अनुसार शेयरों के इंडेक्स नंबर)

क्रम	कंपनी	आधार वर्ष १९८०-८१	१७ जून, १९८७	१२ जून, १९८७	५ जून, १९८७	१७ मई, १९८७ एक मास पूर्व
१.	एल्यूमीनियम	१००.००	२२७.१९	२२०.३४	२१९.५९	२४०.४३
२.	आटोमोबाइल	१००.००	३०२.२०	३००.६९	२९५.५३	३०३.८९
३.	काटन टेक्सटाइल	१००.००	११७.४९	११६.८९	११५.१४	११७.५३
४.	सीमेंट	१००.००	१९३.७१	१९३.०९	१९२.१५	१९८.०६
५.	रसायन	१००.००	२७२.६१	२७३.२०	२६९.९८	२८४.३१
६.	इंजीनियरिंग	१००.००	२५५.०८	२५८.९०	२५४.४६	२६८.९१
७.	बिजली के सामान	१००.००	१६९.३०	१६८.४४	१७१.९७	१८६.७१
८.	खाद	१००.००	२७३.३२	२७४.३८	२७१.६२	२७४.०४
९.	लोहा एवं इस्पात	१००.००	८६७.६३	८७५.२०	८५६.२६	९०८.५५
१०.	कृत्रिम धागे	१००.००	१४१.२५	१४२.९३	१४०.२४	१४३.४४
११.	कागज और कागज के सामान	१००.००	१०४.४७	१०४.५२	१०५.२२	१०९.४७
१२.	चीनी	१००.००	१४२.०६	१४०.८९	१४०.८९	१४१.७१

सूखा

अशुभ संकेत

उत्तर भारत के आठ राज्य मानसून के धोखा देने के कारण अकाल का सामना करेंगे, तो पूर्वी भारत के चार राज्यों में अतिवृष्टि से फसल चौपट हो रही है। ८० सालों में पहली बार प्रकृति का ऐसा भीषण प्रकोप हुआ है, जबकि देश के राजनीतिक हालात अनिश्चित हैं और समूचा अर्थतंत्र डगमगा रहा है। ऐसी स्थिति में अकाल की विभीषिका क्या कहर ढायेगी और करोड़ों लोगों को भूख-प्यास से बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें क्या इंतजाम कर रही हैं?

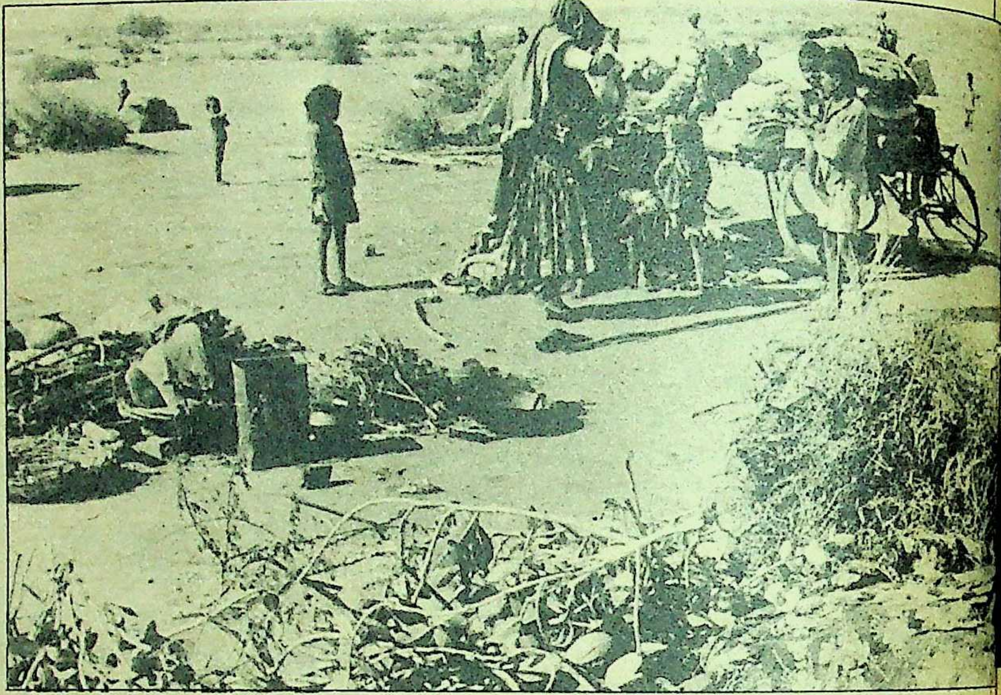

अकाल की दस्तक : अनाज और पानी की तलाश में भटकते लोग

छाया : गोपाल संगर

खरीफ की देर से बुआई अथवा बिन जोते-बोये खेत, हड्डियों के ढांचे हुए भूखे-प्यासे मवेशी और आकाश की ओर टकटकी लगाये ईश्वर से प्रार्थना करते असहाय किसान—यह एक सामान्य चित्र है, १९८७ के उत्तर भारत के सूखे का। शहरों की बिजली आपूर्ति में रोजाना की कटौती, भाखड़ा नहर जलाशय के जलस्तर में क्रमशः गिरावट से अपर्याप्त जल आपूर्ति और कस्बों-शहरों में दूध और सब्जियों का जबर्दस्त अभाव-सूखे की भयावहता और बढ़ा रहा है।

आधिकारिक अनुमान भी भयावह हैं। खाद्यान्नों, चावल, दालों और विशेषकर कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारी कमी निश्चित है। पूरे वर्ष पानी का अभाव उनकी नियति बन जायेगा जो देश के सूखाग्रस्त भाग में रहते हैं। इसका अर्थ है कि अवश्यभावी रूप से पानी से बननेवाली बिजली (पनबिजली) में गिरावट आयेगी।

यह स्थिति आगे चलकर हमारे जीवन को कितना दुष्कर बनायेगी आसानी से समझा जा सकता है। बेरोजगारी बढ़ेगी, अनाज, बिजली और जल दुर्लभ होता चला जायेगा।

सूखे केंद्र सरकार की किस्मत का भी फैसला करते हैं। स्मरण कीजिए १९८० में प्याज की आसमान छूती कीमतों ने जनता सरकार की प्रतिष्ठा गिरा दी थी। मंहगी प्याज से धनी-निर्धन दोनों वर्गों पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि धनी जहां इसे सलाद और सुस्वादु भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, वहीं गरीब इसकी मदद से सूखी रोटी हलक के नीचे उतारता है, खासकर तब जब आलू या दालें उसकी आय से बहुत मंहगी होती हैं।

सूखे का इसीलिए अपना राजनैतिक अर्थतंत्र होता है। उस स्थिति में तो और भी, जब सरकार अपनी विश्वसनीयता तेजी से खोती जा रही हो। एक ऐसा नेतृत्व जो बोफोर्स या फेयरफैक्स ख्याति के व्यापक भ्रष्टाचारों से आकंठ डूबा हो, पर इन आरोपों की भारी संभावना है कि वह अर्थव्यवस्था को चौपट करने और मध्यम वर्ग, निर्धनों और मोहताजों का जीवन दूभर बनाने के लिए वही जिम्मेदार है। बढ़ती मंहगाई और रोजगार की संभावना में कमी से हड़तालों, प्रदर्शनों तथा बंद आदि का तांता लगना अवश्यंभावी है। और अनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रायः सरकार को वेतन वृद्धि पर रोक लगाने को उद्यत करती है (यद्यपि मूल्य वृद्धि जारी रहती है)। इससे प्रभावित वेतन अर्जकों में संगठित प्रतिरोध की प्रबल भावना जागृत होती है। उनके लिए विकल्प होते हैं, सड़कों पर उतरना या हड़तालों का सहारा लेना। शांति-व्यवस्था बनाये रखना और दुष्कर हो जाता है और जब कभी पुलिस को छूट दी जाती है तो असंतोष और गहन तथा व्यापक हो जाता है।

मूल्यवृद्धि शुरू : वस्तुतः सूखे का असर दीखने लगा है। सब्जियों के दाम दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। मसलन टमाटर अगस्त के पहले पखवारे में, दिल्ली के कुछ भागों में १६ रु० किलो बिक रहा था जबकि लगभग एक पखवारे पूर्व उसका दाम १० रु० से कम था। अगस्त के दूसरे सप्ताह में दूध का दाम ६ रु० लीटर, सरसों का तेल २८ रु० किलो और प्याज ५ रु० से अधिक और मामूली साग-सब्जी ४ रु० किलो या अधिक दाम पर बिक रही थीं।

आलू की कीमत इस वर्ष अपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गयी है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में यह ५ रु० किलो था जिसके सितंबर के प्रथम सप्ताह में ८ रु० पहुंचने की संभावना है। तिलहनों का थोक बाजार मूल्य १० अगस्त को ६० रु० क्विंटल बढ़ गया था और सभी अनाजों के मूल्यों में वृद्धि के संकेत थे। यह मूल्य वृद्धि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद हुई कि अनाजों की कमी की संभावना नहीं है। सरकार का कहना है कि वह २ करोड़ ३० लाख टन का अपना संपूर्ण सुरक्षित भंडार आवश्यकता पड़ने पर बाजार में पहुंचा देगी ताकि अनाज की कीमतें अंधाधुंध न बढ़ सकें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब तबकों को अकाल की स्थिति से बचाने के लिए अनाज के रूप में सूखा राहत उपलब्ध कराना आवश्यक हो जायेगा।

जहां तक मूल्यों का संबंध है, ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा सुरक्षित भडार जारी करने से व्यापारियों के मनमाना मूल्य वृद्धि में

बिन पानी सब सून

कठिनाई होगी। किंतु कीमतों में अत्यधिक वृद्धि अवश्यंभावी होगी क्योंकि अभाव का मनोविज्ञान और वास्तविक अभाव का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति थोक विक्रेता के हित में होगी। वह सट्टेबाजी, जमाखोरी और नियंत्रित आपूर्ति का सहारा लेगा। अनाजो की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद खाद्यान्नों का मूल्य इन दिनों जिस तेजी से बढ़ रहा है वह इसका प्रमाण है कि कुछ व्यापारियों को आगामी दिनों की कमाई का अहसास हो गया है और वे और मूल्यवृद्धि के पूर्व भरसक खरीद कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में जमाखोरी का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है।

यदि मानसून पूर्णतया न आया तो रबी फसल को गंभीर खतरा होगा। अधिकांश फसलों की सिंचाई भूगर्भीय जल से करनी पड़ेगी जबकि पानी का स्तर सूखे के कारण बहुत नीचा होगा।

इससे सर्दी के दिनों में पैदा होनेवाली सब्जियों पर भी प्रभाव पड़ेगा और कीमतों पर पड़ने वाले असर की तोबात ही छोड़ दीजिए। इससे तिलहनों की पैदावार सर्वाधिक प्रभावित होगी। गुजरात वनस्पति तेल के लिए बड़ी मात्रा में मूंगफली की आपूर्ति करता है, लेकिन सूखे के कारण वहां भी तिलहन का उत्पादन सामान्य पैदावार के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, मूंगफली का अन्य आपूर्तिकर्ता है, वह भी भयंकर सूखे से पीड़ित है। यही हाल प०उ०प्र० और पंजाब का भी है। सरकार पहले से ही तिलहनों या खाद्य तेलों के एकमुश्त आयात पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसका अध्ययन किया जा रहा है कि इस बढ़े विदेशी मुद्रा भार का प्रभाव उद्योग के लिए आयात किये जाने वाले सामानों पर क्या पड़ेगा। कहा जाता है कि उद्योग धंधे संबंधी सामानों विशेषकर भारी मशीनों और इलेक्ट्रानिक्स के साज-सामानों के आयात को तिलांजलि ही देनी पड़ेगी।

उद्योग धंधों पर प्रभाव : यह औद्योगिक उत्पादन में कटौती के कारणों में से एक को स्पष्ट करता है। दूसरे शब्दों में लोगों को भोजन व अन्य आवश्यक जिसें उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक आयातों, खासकर पूंजीगत सामानों, में भारी कटौती करनी पड़ेगी। औद्योगिक उत्पादन में कमी के अन्य कारण अवश्य ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें पनबिजली की कमी प्रमुख है। इस मामले में महाराष्ट्र के प्रभावित होने की संभावना नहीं किंतु गुजरात को लगभग पूर्णतया महाराष्ट्र पर निर्भर होना पड़ेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, उ०प्र०, राजस्थान, म०प्र० व दिल्ली तो स्थानीय पनबिजली आपूर्ति से पूर्णतया रहित रहेंगे। दूसरे शब्दों में देश के बिजली संचालित प्लांटों का कम से कम एक चौथाई या पांचवां भाग इससे प्रभावित होगा।

किंतु उद्योग का सबसे बड़ा शत्रु होगा कदाचित् मांग पक्ष। निरंतर बढ़ते फर्टीलाइजर (रासायनिक खाद) उद्योग को मांग की भारी कमी का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि किसान पर्याप्त सिंचित जल उपलब्ध न होने पर इसका कम मात्रा में उपयोग करेंगे। इसके साथ ही मंझोले या गरीब किसान परिवार को खरीफ फसल के अभाव में पूंजी की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। इससे वह कृषि-सामान खरीदने की स्थिति में नहीं रहेगा। नतीजतन जिस एक प्रमुख जिस पर किफायत का बोझ पड़ेगा, वह फर्टीलाइजर ही होगा। इस प्रकार फर्टीलाइजर के उपयोग में लगभग १५ से २० प्रतिशत की कमी लाजिमी लगती है।

जिस दूसरे प्रमुख सामान के इस्तेमाल में कमी आयेगी वह है, कपड़ा उद्योग के उत्पाद। इसमें सस्ते मोटे कपड़े से लेकर ग्वालियर रेयान, बाम्बे डाइंग या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी फर्मों के ऊंची कीमत वाले सेंथेटिक उत्पाद आयेंगे। केवल ऊंची कीमत पर बिकने और उच्च आय वर्ग के प्रयोग में आने वाले उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी किस्म के कपड़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह होगी, वास्तविक आय में गिरावट जिससे तमाम वर्गों के लोगों का हाथ तंग रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मकानों का निर्माण और भी प्रभावित होगा। क्योंकि मध्यम व उच्च आय वर्ग द्वारा उत्पादित जिसों के मूल्यों में तुलनात्मक वृद्धि के बावजूद उनकी बचत काफी घट जायेगी। घटी हुई आय और बढ़ी हुई मूल्य दर से उनके पास बचाने को रहेगा क्या?

सीमेंट उद्योग में तो मांग की और मंदी का दौर आने जा रहा है। उद्योग के नेताओं ने सरकार से संरक्षण के कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि वह अपने उत्पादन का दो तिहाई भाग भी बेच नहीं पा रहे हैं। पारिवारिक बचत में गिरावट की क्षतिपूर्ति संभव थी यदि सरकार योजना की राशि से अधिक खर्च निर्माण कार्यों, मसलन बड़े पैमाने पर शहरी आवास, इमारतें, पुल, सड़क आदि पर करने की स्थिति में होती। किंतु सरकार इसके विपरीत सूखा पीड़ित गरीबों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कोष की भयंकर कमी का सामना कर रही है। इस मद में ५६०० करोड़ का प्रावधान पूर्णतया अपर्याप्त है। इसलिए अब किसी भी उद्योग को सरकार से किसी आर्थिक सहारे (मसलन उसके उत्पादों की बडी मात्रा में खरीद) की आशा नहीं है।

अन्य प्रभाव : जहां तक सामान्य और चौमुखी मूल्यवृद्धि का संबंध है, स्पष्ट है कि मुख्य प्रवर्तक होगा अनाज। यदि भोजन, वस्त्र और आवास और महंगा हो गया तो श्रमिकों

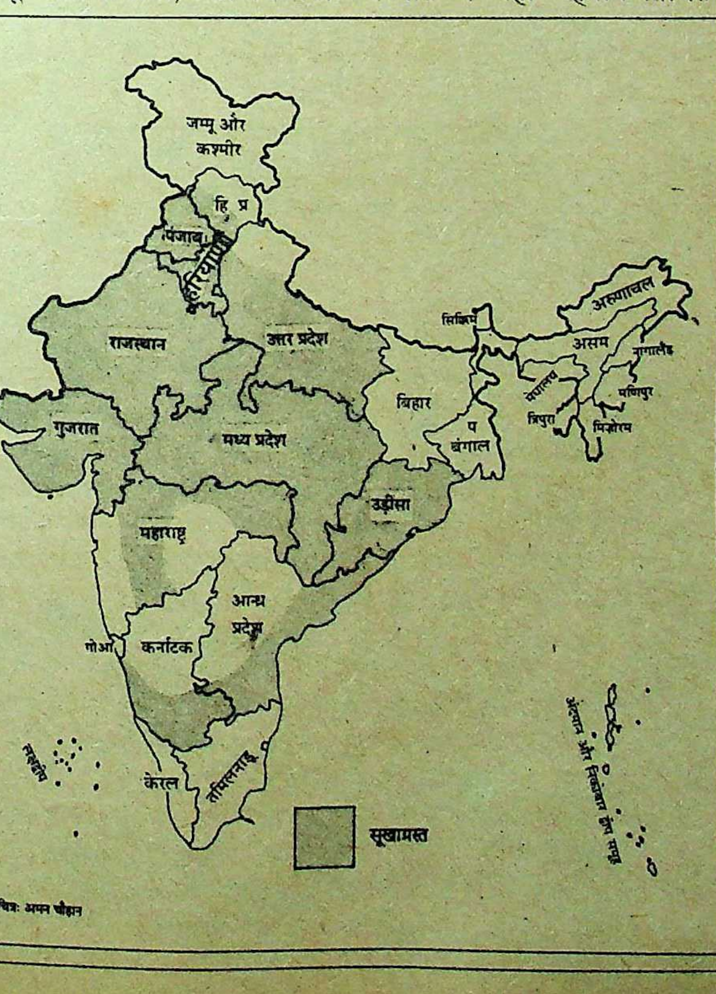

मानचित्र: अमन चौहान

को किसी भी सूरत में अधिक वेतन देना होगा जिसके बिना न उनके अस्तित्व की सुरक्षा संभव होगी और न उनमें आवश्यक कार्यक्षमता ही शेष रहेगी। कोई भी उद्योग नहीं चाहेगा कि उसके श्रमिक न्यूनतम पोषाहार के अभाव में कम उत्पादक बनें। इसलिए सामान्य वेतन वृद्धि होगी और उसी समय पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें वेतनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेंगी। किसी भी सूरत में इससे औद्योगिक लागतों और सरकारी खर्चों का बढ़ना लाजिमी है। इस प्रकार एक जबर्दस्त दबाव आयेगा जिसे अर्थशास्त्री 'मूल्य दबाव स्फीति' कहते हैं। शेष परिदृश्य की कल्पना तो आसानी से की जा सकती है। लागतें बढ़ेंगी और मूल्य बढ़ेंगे, फिर उसके परिणामस्वरूप लागतें फिर बढ़ेंगी और कीमतें और बढ़ेंगी और यह दुष्चक्र जारी रहेगा।

यह स्थिति रोजगार में वृद्धि की किसी भी संभावना को धूमिल करने में सहायक होगी। दरअसल औद्योगिक और कृषि उत्पादन में कमी की स्थिति से बेरोजगारी बढ़ती ही है। जिनकी आय पहले से ही बहुत कम है उनकी इस साल उससे भी कम हो जायेगी (जैसे, खेत मजदूर और ग्रामीण औद्योगिक मजदूर, मसलन बुनकर, कुम्हार, लोहार आदि) इसलिए उन्हें राहत उपलब्ध कराना होगा। इसका अर्थ होगा किसी सरकारी परियोजना में कम मजदूरी पर काम दिलाना जिसमें कभी नकद और कभी अनाज के रूप में भुगतान करना होगा। किंतु उपलब्ध सरकारी कोषों से कितनों को रोजगार दिया जा सकता है? यदि आप एक व्यक्ति को ८ घंटे काम के एवज में ५ रु० अदा करें तो प्रति व्यक्ति प्रति माह १५० रु० की जरूरत होगी। यदि आप ५६०० करोड़ की यह समूची धनराशि इस मद में खर्च कर दें तो १२ करोड़ लोगों को मात्र तीन माह के लिए रोजगार मिलेगा। और यदि सूखे की भयावह चपेट में ग्रस्त आठों राज्यों की आबादी पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि प्रभावित निर्धनों की संख्या २० करोड़ से कम नहीं है।

राजनीतिक नतीजे : इससे राजनैतिक स्तर पर होने वाले उथल-पुथल का समुचित अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों की जिंदगियों को बरकरार रखने में विफल सरकार के खिलाफ भूख हड़तालें, उग्र विरोध, प्रदर्शन, व्यापक भर्त्सनाएं कदाचित भावी पृष्ठभूमि की एक झलक है। इस पृष्ठभूमि में सरकार से इस्तीफे की मांग को निश्चित रूप में और बल मिलेगा। किंतु सत्ताधारी पार्टी ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव का जोखिम नहीं उठायेगी। वह अपने कोष और सामान एकत्र कर बहुसंख्यक लोगों को अधिकतम संभव राहत उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए वह उन लोगों से विदेशी सहायता तक ले सकती है जिन पर अब तक सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को अस्थिर करने के प्रयास का आरोप लगाया जाता रहा है, क्योंकि हरेक को पता है कि सरकार के खिलाफ क्रोध को समर्थन में भली-भांति बदला जा सकता है। यहां तक कि भ्रष्टाचार के कांडों को भी भुलाया जा सकता है। बशर्ते, भुखमरी के शिकार लोगों को ऐसे मौके पर भोजन मिलता रहे, जबकि इसकी उन्हें रत्ती भर आशा न हो। प्राकृतिक विपदाएं प्रायः सरकार को अपदस्थ कर देती हैं, किंतु वे व्यापक समर्थन का एक आधार भी प्रस्तुत करती हैं, यदि संकट का मुकाबला बुद्धि-विवेक और निपुणता से किया जाये।

हवा का रुख अंततः किस ओर होगा, इसकी दो टूक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वैसे सरकार के गंभीर विपत्तिग्रस्त होने की संभावना उसके शक्ति सुदृढ़ीकरण से दस गुना अधिक प्रतीत होती है। एक बात बहरहाल तय है कि मौजूदा हालात में पहला आघात स्थिरता पर होगा। विडंबना तो यह है कि सूखा जो प्रकृति की उच्छृंखलता की एक प्रत्यक्ष सृष्टि है, देश की सरकार और राजनीति को अस्थिर करने के लिए तत्पर है। क्या इसमें भी कोई विदेशी हाथ है?

> **सूखा जो प्रकृति की उच्छृंखलता की एक प्रत्यक्ष सृष्टि है, देश की सरकार और राजनीति को अस्थिर करने के लिए तत्पर है।**

—अर्थ विज्ञानी

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक

रसायनवटी

बढ़ती हुई आयु, रोज़मर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर पूरे शरीर का पोषण कर पूर्ण सशक्त बनाती है। **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ, विश्वसनीय, असरदार एवं बेजोड़ आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो आयु के हर आयाम पर सतत निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

रसायन वटी
रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
शीतल प्रसाद एण्ड संस
23, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

200 गोली पैकिंग रु. 70/-, 60 गोली पैकिंग रु. 27/50 स्थानीय कर अलग। स्थानीय विक्रेता से लें या वी.पी. द्वारा मंगवायें। वी.पी. खर्च रु. 10/- अलग।

निर्माता :
राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23 दरियागंज, नई दिल्ली– 110002
शाखाएं : दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

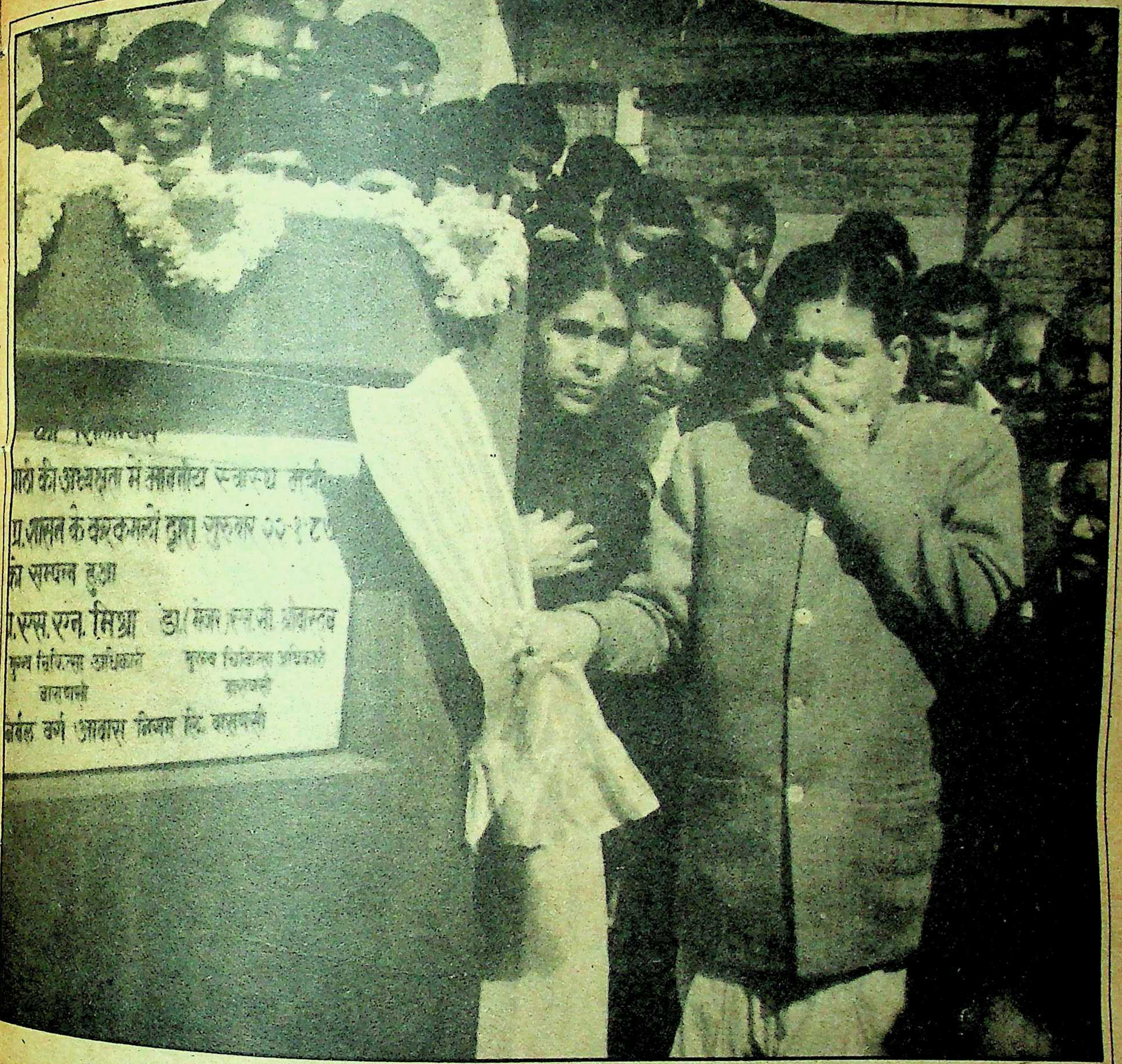

आप सोचते होंगे, इस भीड़ में एक ही व्यक्ति अपने नाक-मुंह पर रूमाल क्यों रखे हुए है? इनको शर्म आ रही है, हंसी आ रही है या दुर्गन्ध महसूस हो रही है? इनमें कौन सी बात सही है, यह तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तथ्य है कि आप उत्तरप्रदेश के साक्षात स्वास्थ्यमंत्री हैं—श्रीयुत लोकपति त्रिपाठी। आप मुगलसराय (वाराणसी) में योजनाधीन निर्बल वर्ग के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास कर रहे हैं। आप राजनीति के पुराने ज्ञाता हैं, मुख्यमंत्री की कुरसी से भी बाल-बाल बचे हुए हैं, सरकार की 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' वाली चाल को भी जानते हैं—इसलिए उनसे छिपा नहीं है कि मात्र शिलान्यास से कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बन जाता, न स्वास्थ्य केन्द्र बन जाने से निर्बल वर्ग का स्वास्थ्य ठीक रखने की कोई गारंटी दी जा सकती है। अतः शिलान्यास के समय ही उन्होंने यह इशारा कर दिया है कि जैसे निर्बल वर्ग की दुर्गन्ध से बचने के लिए 'सरकार' नाक पर रूमाल रखे हुए है, वैसे ही निर्बल वर्ग को यदि माहौल की गंदगी से बचना हो, तो अपने लिए नाक पर रखने के लिए कपड़े की व्यवस्था कर ले। एक स्वास्थ्य मंत्री इससे बढ़कर और नेक सलाह क्या दे सकता है!

डा० शंकर दयाल शर्मा

महाराष्ट्र के राज्यपाल डा० शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गये हैं। भारत के एक प्रतिनिधिमण्डल के नेता बनकर १२ अगस्त को मास्को जाते समय उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी कि एक सप्ताह बाद १९ अगस्त को अपने ७०वें जन्म दिन पर वह भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके होंगे। इसकी जानकारी उन्हें उस समय भी नहीं थी जब मास्को में उन्हें दिल्ली लौटने का संदेश मिला था और १७ अगस्त को वह कांग्रेस महासचिव नवल किशोर शर्मा के साथ दिल्ली की उड़ान पर बैठ गये थे।

डा० शर्मा के दिल्ली पहुंचते ही राजीव गांधी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव सत्ता और प्रतिपक्ष की आम सहमति से करने के लिए सदन के विपक्षी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बातचीत का आमंत्रण पाकर हड़बड़ी में विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मिलने से पूर्व आपसी बातचीत में अपनी ओर से अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती और लोकदल नेता सैयद मीर कासिम के नाम चुने। उस समय तक अटकलों के गर्म माहौल और सत्तारूढ़ दल के प्रति बढ़ते विपक्षी अविश्वास के चलते उपराष्ट्रपति पद के कई उम्मीदवारों के नाम सुर्खियों में आते-जाते रहे थे। इनमें केंद्रीय नगर विकासमंत्री मोहसिना किदवई से लेकर इंका से निष्कासित सांसद आरिफ मोहम्मद खां, पं० बंगाल के राज्यपाल प्रो० नूरुल हसन, गृहमंत्री बूटा सिंह, लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ और सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के नामों की एक लंबी फेहरिस्त चलती रही। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में घटनाक्रम इस ढंग से बदला कि केवल १२ घंटे में एक नया नाम सामने आया और उसे आम सहमति मिल गयी।

विपक्ष की सहमति : उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए यह चुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए राष्ट्रपति के चुनाव से कम महत्व का नहीं था। बोफोर्स सौदे में दलाली और राष्ट्रपति चुनाव से लेकर बोफोर्स प्रकरण पर संसदीय समिति के गठन को लेकर हुई बहस, सत्ता और विपक्ष के तनते रिश्तों को देखते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से प्रत्याशी के चयन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गयी थीं। ऐसे में अचानक शंकर दयाल शर्मा के नाम पर विपक्ष की तुरंत सहमति लोगों के लिए रहस्यमय नहीं, तो आश्चयेजनक अवश्य थी।

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इंका के संभावित प्रत्याशियों की ओर संकेत करते हुए राज्यपालों में प० बंगाल के नूरुल हसन, हरियाणा के एस०एम०एच० बर्नी और महाराष्ट्र के डा० शंकर दयाल शर्मा, न्यायिक सेवा के अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती, सक्रिय राजनीतिकों में गृहमंत्री बूटा सिंह और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के नाम लिये थे। इनमें पी०एन० भगवती और नूरुल हसन के नाम इंका सूची में सर्वोपरि थे। इन परिस्थितियों में मुस्लिम लीग और अन्ना डी०एम०के० को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों के नेता अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श पर बैठे। इनमें अटल बिहारी बाजपेयी, निर्मल चटर्जी, अजीत सिंह, बलवंत सिंह रामूवालिया, मधु दंडवते, पी० उपेंद्र, गुरुपद स्वामी, लालकृष्ण आडवाणी सहित १८ नेता शामिल थे। इस बैठक में पी०एन० भगवती और डा० शंकर दयाल शर्मा के नामों पर विपक्ष ने अपनी राय बनायी।

शाम साढ़े चार बजे प्रधानमंत्री के साथ विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने पी०एन० भगवती और डा० शंकर दयाल शर्मा के नामों में से किसी एक के चयन पर अपनी सहमति दे दी। इसके पहले उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों में बलराम जाखड़ का नाम सबसे पहले कट चुका था। प्रसिद्ध इतिहासकार नूरुल हसन के नाम पर मुस्लिम सांसदों में ही मैतक्य नहीं था। अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति पी०एन०भगवती के नाम पर स्वयं इंका आलाकमान का सोचना था कि राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा रखनेवाले न्यायिक सेवाओं के लोगों को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल एम०एस०एच० बर्नी का आडवाणी और गुरुपद स्वामी ने खुलकर विरोध किया। चुनाव की इस प्रक्रिया में बूटा सिंह के साथ विपक्ष की पूरी सहानुभूति होने के बावजूद उनका नाम डा० शंकर दयाल शर्मा पर बनती आम सहमति के कारण पीछे हो गया। कांग्रेस में एक मत यह भी था कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने पर न हिंदू प्रसन्न होंगे और उनके मजहबी सिख होने के कारण न ही सिख।

मधु दंडवते व अन्य विपक्षी नेताओं से 'माया' ने जब यह जानना चाहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया, तो उनका उत्तर था कि अब तक सभापति बहुमत का ही चुना जाता रहा है। हमारे सामने प्रत्याशी खड़ा करने से बड़ा सवाल ऐसे व्यक्ति के चुनाव का था, जिसमें राज्यसभा चलाने की बेहतर क्षमता और संसदीय नियमों की अच्छी जानकारी हो, ताकि विपक्ष द्वारा उठाये गये वैज्ञानिक मुद्दों पर विपक्ष को उसकी योग्यता का लाभ मिल सके।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम सरकार के मुख्यमंत्री रामाराव को तत्कालीन राज्यपाल द्वारा अपदस्थ करने के बाद शंकर दयाल शर्मा द्वारा वहां का राज्यपाल बनते ही रामाराव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के कारण भी विपक्ष उनकी निष्पक्षता का कायल था।

डा० शर्मा का व्यक्तित्व : महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर डा० शंकर दयाल शर्मा की पहली नियुक्ति १९५२ में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हुई। कैंब्रिज विश्वविद्यालय से कानून का अध्ययन किये डा० शर्मा १९५६ तक इस पद पर रहे। भोपाल राज्य से मध्य-प्रदेश बनने पर वह पहले मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने।

वह १९७१ में लोकसभा सदस्य चुने गये। १९७२ से ७४ तक डा० शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। १९७४ से ७७ तक केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में काम करने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रामाराव की ऐतिहासिक बर्खास्तगी के कारण १९८४ में रामलाल की जगह उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। कांग्रेस के गहराते संकटों के दौर में काम आनेवाले शंकर दयाल शर्मा को १९८५ में आंध्र प्रदेश से पंजाब का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। आतंकवाद से सुलगते पंजाब की गवर्नरी डा० शर्मा को बहुत महंगी पड़ी। इसके चलते उन्हें दिल्ली में अपनी बेटी गीतांजलि और दामाद इंका सांसद ललित माकन की निर्मम हत्या का दुख झेलना पड़ा। निरंतर पड़ाव बदलने के घटनाक्रम से जुड़े डा० शर्मा १९८६ में महाराष्ट्र के राज्यपाल बनकर बंबई गये और दो वर्ष से कम समय में ही एक बार फिर उनका दायित्व बदला। अब वह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा संचालन का दायित्व भी उन्हीं पर है, अपने कार्य संचालन में उन्हें सबसे बड़ी सहूलियत यही होगी कि उन्हें विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिलेगा।

—दिलीप कुमार

संस्थापक : स्वर्गीय-श्री क्षितीन्द्रमोहन मित्र। सम्पादक : आलोक मित्र। श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली—११०००१।

2 3/9/8
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

डायमंड पाकेट बुक्स में

संघर्ष की अपार सफलता के बाद
लाखों पाठकों के प्रिय उपन्यासकार
समीर
का नया उपन्यास
बेवफा
प्यार में बेवफाई की
एक दर्द भरी दास्तान

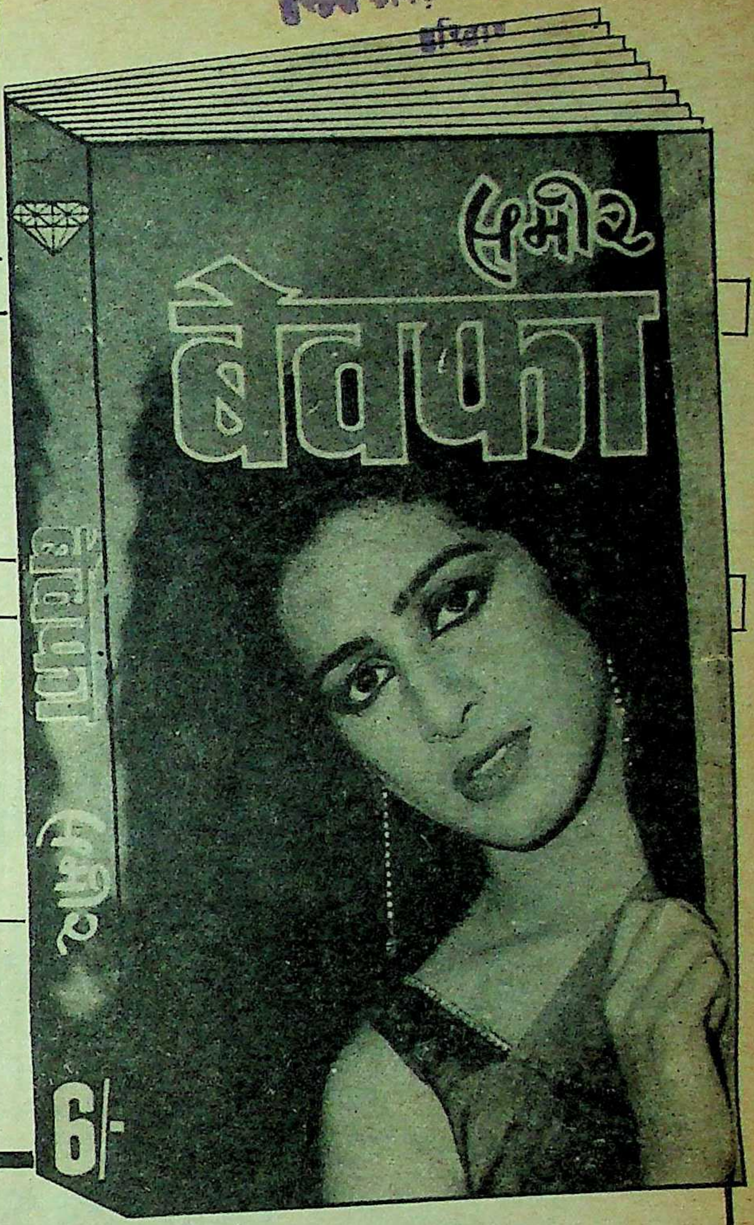
समीर
बेवफा
बेवफा
समीर
6/-

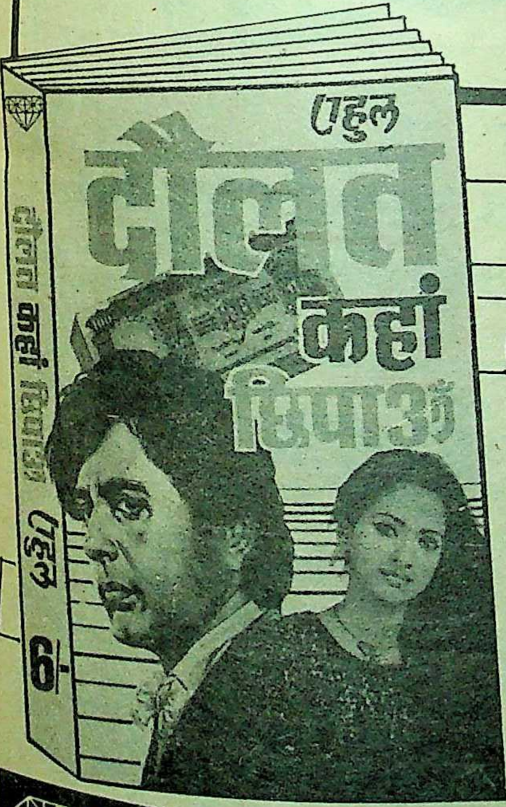
राहुल
दौलत कहां छिपाऊँ
दौलत कहां छिपाऊँ
राहुल
6/-

सस्पैंस थ्रिल और एक्शन से भरपूर
राहुल का नया रोमांचकारी उपन्यास
दौलत
कहां छिपाऊँ
6/-

डायमंड कामिक्स प्रा.लि. 2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

Mediamind

फ़ैरेक्स®
पहली पसंद!

नया विकसित फ़ैरेक्स®
आपके शिशु के लिए ठोस आहार की एक आदर्श शुरूआत.
क्योंकि शिशु-विकास के लिए इसमें अनुकूल तत्त्व हैं.

प्रोटीन और फ़ैट (चिकनाई) का उचित मिश्रण,
प्रोटीन से भरपूर फ़ैरेक्स शिशु के स्वस्थ विकास में मदद करता है. नया विकसित फ़ैरेक्स शिशु की कोमल पाचन शक्ति के अनुकूल ख़ास तौर से बनाया गया है. जिसमें फ़ैट (चिकनाई) का उपयुक्त मात्रा में समावेश है.

स्वस्थ रक्त के लिए पर्याप्त आयरन
शिशु के शरीर में जमा आयरन (लौह) चौथे महीने तक ख़त्म हो जाता है. फ़ैरेक्स में पर्याप्त आयरन है ताकि शिशु का रक्त स्वस्थ रहे, और बीमारियों से मुक़ाबला करने में उसे मदद मिले.

कैल्सियम–फ़ॉस्फ़ोरस का आदर्श अनुपात
शिशु के दाँतों व हड्डियों के मज़बूत और स्वस्थ विकास के लिए कैल्सियम और फ़ॉस्फ़ोरस ज़रूरी हैं, इसी लिए फ़ैरेक्स में कैल्सियम-फ़ॉस्फ़ोरस का २:१ आदर्श अनुपात रखा गया है.

फ़ैरेक्स का प्रत्येक आहार अब ज़्यादा स्वादिष्ट है. मिलाने में ज़्यादा आसान है.

New Improved
Farex®
CEREAL WITH MILK

दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं!
बस पानी के साथ मिलाइये और खिला दीजिये.

नया विकसित फ़ैरेक्स®

CLARION/B/GX/15/244/HIN

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक १८

३० सितंबर, १९८७

माया

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ : अजय कुमार
विशेष संवाददाता
दिल्ली : राहुल देव
पटना : विकास कुमार झा
संवाददाता
दिल्ली : पुनीत टंडन
लखनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल : सुधीर सक्सेना
जयपुर : ओम सैनी
कला निदेशक :
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा :
आर० एन० सिन्हा

• प्रधान कार्यालय : २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ०५४०२८०, • दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स : ०३१,६१७१५ ▪ लखनऊ कार्यालय : बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन : ३६२६८/३४४७७▪पटना कार्यालय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, भोपाल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्ताना-बाद, भोपाल १७ फोन : ६५९६८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, टेलेक्स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय : स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन : २९९०३५

"Air Surcharge 50 Paise Per copy" Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Imfal, Tejpur, Shilong, Dimapur & Kathmandu and 25 Paise Agartala.

यह अंक

आवरण कथा

माया
ठाकुर बनाम ब्राह्मण:
शामत राजाओं की या राजीव की ?
विकल्प की तलाश में विपक्ष

२६

पं० कमलापति त्रिपाठी ने जब से भूतपूर्व राजाओं पर राजीव गांधी का तख्ता पलटने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है, तब से कांग्रेस-इ में ब्राह्मण नेताओं और ठाकुर नेताओं के बीच वाग्युद्ध शुरू हो गया है। क्या भूतपूर्व राजाओं को कांग्रेस-इ से निष्कासित किया जायेगा ? जातिवादी मानसिकता और भूतपूर्व राजाओं के बिना राजीव गांधी को किस समस्या का सामना करना पड़ेगा ?

अमेठी

अमेठी के राजकुमार संजय सिंह की बगावत के बाद क्या अमेठी के मतदाता भी राजीव गांधी के विरुद्ध होते जा रहे हैं ? 'माया' टीम का सर्वेक्षण : १४

मध्य प्रदेश

क्या दिल्ली दरबार ने मोतीलाल वोरा को बदलने का मन बना लिया है ? सांसद कमलनाथ इन दिनों वोरा की खिंचाई में क्यों लगे हैं ? ७३

राजस्थान

लगातार चार सालों से मानसून की प्रतीक्षा करते राजस्थान की वर्तमान सूखे ने क्या दशा बना दी है ?

५०

बनारस

क्या वी०पी० सिंह की बनारस यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि पं० कमलापति त्रिपाठी का अपने ही गढ़ में कोई असर नहीं है ? ४२

साक्षात्कार

लंबी चुप्पी के बाद राजीव गांधी के बचाव के लिए फिर से सक्रिय हुए भारतीय राजनीति के चाणक्य द्वारिका प्रसाद मिश्र का विशेष साक्षात्कार : ३८

जिंदा

पुलिस के लिए भी आतंक बन गया कुख्यात आतंकवादी जिंदा कैसे पकड़ा गया और वह कौन से रहस्य उगल रहा है ?

८६

दिल्ली दरबार : लगना वामपंथी मुखौटे का ! ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
फोटोफीचर ९
बेढब १३
देश : विकल्प की तलाश में बदहवास विपक्ष २०
बिहार : किधर जायेगा बिहार ? ५३
महाराष्ट्र : सन '४२ की वापसी ! ५८
कार्टून ७२
तथ्य-कथ्य ७६
विदेश : रियाद : कार-प्रेमियों का स्वर्ग ७८
विदेश : रियाद में भारत ८१
पड़ोस : 'जीये सिंध' के नेता जी०एम० सैयद से बातचीत ८४
घटनाक्रम : 'इंडियन एक्सप्रेस' पर छापा : पोल खोलने की सजा ८८
उद्योग : अब मोदी और बिड़ला आमने-सामने ९१
परदे के पीछे ९४
दूरदर्शन : मंडी हाउस में पहुंच का फल ९७
तथाकथित : मुलायम सिंह का क्रांति रथ १००
लोग १०४

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

समय ही सच्चा निर्णायक

‘माया’ ३१ अगस्त, ’८७ ‘संसद में बोफोर्स’ पढ़ा। संख्या के बल से समर्थ सरकारी पक्ष इस मामले को चाहे दबा दे, परंतु समय इसके परिणाम को बिना बताये नहीं रहेगा। देश की जनता इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझ गयी है। संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन सत्ता पक्ष से किया जाना बेमानी है। हर कीमत पर संसद की गरिमा को बनाये रखा जाना चाहिए। जो सदस्य संसद की मर्यादा भंग करते हैं, केवल वे ही दोषी नहीं हैं, बल्कि उनको चुनकर भेजनेवाले भी उतने ही दोषी हैं।—त्रिलोकीनाथ यादव, मुसहा, कुर्दह, बस्ती

वी०पी० सिंह और विपक्ष

लेख ‘वी०पी० सिंह और विपक्ष’ (३१ अगस्त) पढ़ा। देश के सभी विपक्षी दल विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने-अपने दल में शामिल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की साफ-सुथरी छवि का लाभ उठाया जा सके।

किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिशाहीन विपक्षी दलों में झांक कर देखने की बजाय स्वयं एक सशक्त विपक्षी दल की स्थापना करना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता में स्पष्टवादी व ईमानदार नेता के रूप में अपनी जगह बना बैठे हैं। देश में सशक्त विपक्षी दल की कमी है। जो विपक्षी दल हैं वे अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। वे जनता के प्रति वफादार कम व अपने ‘घर व स्वार्थ’ के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। सभी विपक्षी दल कुरसी की भूख के आगे रचनात्मक कदम उठा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह को सशक्त दल तैयार कर एक मुहिम चलानी चाहिए। —श्रीमती हेमलता उपाध्याय, घिनोदा (खाचरौद)

आज का मिथिलांचल

‘माया’ १५ अगस्त, ’८७ के अंक में ‘आज का मिथिलांचल’ शीर्षक वाली रपट में विकास कुमार झा द्वारा सही रूप प्रस्तुत किया गया है। सचमुच मिथिलावासी अपनी सांस्कृतिक चेतना भूलकर आधुनिकता के झूठे लिबास में फंस गये हैं।

यह बात सही है कि मिथिलावालों की एकमात्र सबसे बड़ी सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था पटना की ‘चेतना समिति’ है, लेकिन यह संस्था भी मिथिला के लोगों की भलाई का कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकी। ‘चेतना समिति’ केवल विद्यापति पर्व मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। —अनिल कुमार दास, पो० दलसिंहपाड़ा, पश्चिम बंगाल

मेरठ सांप्रदायिकता का केंद्र क्यों बना ?

‘माया’ ३१ अगस्त की पत्रिका में प्रकाशित ‘मेरठ सांप्रदायिकता का केंद्र क्यों बना ?’ पढ़कर अत्यंत दुख हुआ। आंखें आंसुओं से भर गयीं। इस देश में हमारे नेता जब तक जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जब तक वोटों की राजनीति चलती रहेगी, तब तक मेरठ ही क्यों और भी शहरों में सांप्रदायिकता पनपती रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता का नारा लगाते हैं, लेकिन इन तथाकथित नेंताओं की गतिविधियों पर रोक क्यों नहीं लगाते। प्रधानमंत्री को चाहिए कि इन सांप्रदायिक नेताओं के मुख से निकलनेवाले विष पर रोक लगायें। —जय प्रकाश भदेशिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

हमने एक और दुश्मन तो पैदा नहीं कर लिया

‘माया’ ३१ अगस्त की विशेष रिपोर्ट ‘खतरों से घिरा साहसिक कदम’ में दिया गया तर्क सही है कि विरोधाभासों से घिरा यह समझौता सफल हो पायेगा या श्रीलंका की जातीय हिंसा जारी रहेगी। नि:संदेह इस समझौते से श्रीलंका में पिछले ४ वर्षों से जारी जातीय हिंसा के ज्वर में ठहराव आया है। इसके साथ ही सकारात्मक तथ्य यह है कि चीन, पाकिस्तान, इस्राइल व अमेरिका आदि के कारण भारत की सुरक्षा पर मंडराते खतरे टल गये हैं। इन सबके बावजूद भी खतरा टला नहीं क्योंकि तमिलों में सबसे उग्रवादी मुक्ति टाइगरों ने आरंभिक विरोध के बावजूद बेमन से इस समझौते को स्वीकार किया है।

इसकी पुष्टि इस संगठन के नेता प्रभाकरण की अनुपस्थिति है। इस समझौते में यह भी स्पष्ट नहीं है कि श्रीलंका और भारत के बीच यदि मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उनका निपटारा कौन व कैसे करेगा ? जाफना में रसद पहुंचाने, बौद्ध भिक्षुओं व श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के साथ समझौते का विरोध, प्रचंड प्रदर्शन व हमला आदि की घटनाओं से यह अंदाजा लगता है कि यह गुत्थी सुलझाना कठिन है। एक डर-सा लगता है कि कहीं हमने एक और दुश्मन तो पैदा नहीं कर लिया

‘हे’ भारत भाग्य विधाता !

‘माया’ के ३१ अगस्त, १९८७ के अंक में प्रकाशित रपट ‘बिहार के विधायकों को जन-गण-मन तक याद नहीं’ पर पाठकों की काफी तीखी प्रतिक्रिया मिली है। हजारों की संख्या में आये पत्रों में से एक ने भी विधायकों के पक्ष में नहीं लिखा है। आलोक वैष्णव (शहडोल, म०प्र०) इसे लोकतंत्र की विशेषता बतलाते हैं ‘अंधाधुंध के राज्य में गदहा पंजीरी खाये।’ आशुतोष शर्मा (भीलवाड़ा, राजस्थान) की सलाह है ‘इन प्रतिभाओं से ऐसे सामान्य ज्ञान की अपेक्षा घूंसेबाजी, गाली-गलौज, चप्पल युद्ध और हंगामे जैसे रोचक विषयों पर जानकारी एकत्र की जाती तो उचित रहता। उनके कोर्स के बाहर के प्रश्न पूछकर ‘माया’ ने विधायकों के साथ अन्याय किया है।’ मुजफ्फरपुर के वीरेंद्र कुमार सिंह विधायकों से बहुत रुष्ट हैं। वह लिखते हैं ‘जो व्यक्ति योग्यता के बल पर चपरासी भी नहीं बन सकता, वोट के बल पर वह ऐश्वर्य भोग रहा है। ऐसे मंत्रियों एवं विधायकों को धक्के देकर निकाल देना चाहिए, लेकिन शायद हमारा संविधान ही ऐसा है।’ अरुण गुटगुटिया (मधुपुर) को शक है कि ऐसे लोग देश का विकास कर सकते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि यदि कहीं एम०ए० का इम्तहान लेने वाला ही अंगूठा छाप हो, तो उन छात्रों का भविष्य भगवान के हाथ में है। गया की रेणुका पालित, ऐसे छोटे प्रश्न पूछना विधायकों और मंत्रियों का अपमान मानती हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं पर बोफोर्स, फेयरफैक्स, बाढ़ और सूखा जैसी ढेरों जिम्मेदारियां हैं, ये इन्हें निपटायें कि जन-गण-मन रटने बैठें।

बिहार से आये ढेरों पत्रों में इन विधायकों को अपनी बदकिस्मती और शर्म का सबब बनाया गया है। उनका कहना है कि इन्हीं के कारण हम अपने को बिहारी कहने में भी शर्माते हैं। वैशाली के अभिमन्यु कुमार ने अपने मार्मिक पत्र में लिखा है ‘इन लोगों की ही कृपा के कारण आज बिहार के लोग दूसरे राज्यों में अपने को बिहारी कहने में संकोच करते हैं।’

इन विधायकों को कोसने के अलावा कुछ पाठकों ने नेक सलाहें भी दी हैं। मसलन, अगर इन विधायकों को यदि सचमुच में भारत से प्रेम है, तो इस्तीफा देकर अपना सामान्य ज्ञान स्तरीय करें और फिर जनादेश प्राप्त करके लौटने का प्रयास करें। भिलाई के दीपक कुमार मिश्रा ने इन विधायकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शिक्षित करने का मशविरा दिया है।

कुछ पाठकों की मांग है कि ऐसा दिलचस्प सर्वेक्षण अन्य क्षेत्रों में भी कराया जाना चाहिए। धनबाद के सुरेश कुमार शर्मा लिखते हैं ‘देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों से इस राष्ट्रगान का सरल रूपांतरण कराया जाये, जिससे इसका अर्थ साफ हो, मगर इसमें ‘दून विद्यालय’ को अलग रखा जाये, क्योंकि उन्हें तो ‘स्वतंत्रता दिवस’ और ‘गणतंत्र दिवस’ में ही अंतर नहीं पता। जमशेदपुर के सिद्धनाथ गुप्ता सहित कई पाठकों ने संसद सदस्यों और अन्य राज्यों के विधायकों में भी ऐसे सर्वेक्षण करवाने की सलाह दी है। एक पाठक का तो दावा है कि भाषा, रहन-सहन और खान-पान में भेद होने के बावजूद मिलनेवाले परिणाम भारत की एकता को प्रदर्शित करेंगे। ■

चिट्ठियां

क्योंकि शरणार्थियों के बहाने हमने बंगलादेश पैदा किया और अब वे ही शरणार्थी असम, बिहार, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में फैलते जा रहे हैं। अतः भविष्य के परिणाम सुखद हों, इसके लिए हमें निःसंदेह इस समझौते के लागू होने में जो कठिनाइयां आती हैं, उनका सही समय पर उचित निपटारा करना होगा तभी हम खतरों से घिरे इस साहसिक कदम को मजबूत बनाकर आगे बढ़ा पायेंगे। —मनो प्रजापति, शास्त्री कालोनी, मंदसौर

शांति पर घातक हमला !

'माया' के ३१ अगस्त अंक की आवरण रपट 'कोलंबो में राजीव पर हमला' पढ़कर यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि क्या यह विश्व नेताओं की नियति है कि जिसने भी सत्य, शांति, एकता, अखंडता और मानवता के लिए कार्य किया, उग्रवाद ने उसे ही अपना निशाना बनाया। इसके लिए ईसा को सूली, सुकरात को विष, महात्मा गांधी, कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, इंदिरा गांधी एवं संत हरचंद सिंह लोंगोवाल को गोलियों का निशाना बनना पड़ा और अब राजीव गांधी के शांति प्रयास पर घातक हमला हुआ। —चंद्रकांत यादव, चांदीतारा, वाराणसी,

शाबाश ! वीरबहादुर

उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी निरंतर १८ माह से यह मांग कर रहे हैं कि महंगाई और मूल्य वृद्धि के कारण उनका वेतन ७५० रुपए कर दिया जाये, परंतु श्री वीरबहादुर की सरकार प्रदेश के उन मजदूरों की जायज मांग को आज तक स्वीकार न कर सकी, जो देश के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देते हैं।

और-तो-और उ०प्र० के अधिकांश सफायी मजदूरों 'जो सेवारत रहकर प्रदेश का नरक साफ कर स्वर्ग बनाते हैं,' को नियमित रूप से सात-माह तक वेतन न उपलब्ध करा पाती हो, उस सरकार ने केवल कुरसी पर रहने के लिए आंख बंद कर विधायकों का वेतन एवं सुख-सुविधा बढ़ाकर प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं किया। यह तो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला हाल हुआ कि जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, उन्हें आश्वासन भी नहीं, और जो दोनों हाथ से जनता व सरकार दोनों को लूटते हैं, उन्हें सर्व सुविधा पुरस्कार। वाह रे वीर बहादुर ! —भुवन संतोषी, वाल्मीकि भंडावर, बिजनौर

राजीव क्या संकट से उबर पायेंगे ?

'माया' ३१ अगस्त की आवरण कथा 'राजीव क्या संकट से उबर पायेंगे', जहां तक मध्यावधि चुनाव का सवाल है राजीव गांधी इसे हरगिज नहीं होने देंगे। मध्यावधि चुनाव का मतलब भारतीय राजनीति में काफी उलट-पलट होना। इसमें कहां क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। हरियाणा का परिणाम देखने के बाद तो राजीव गांधी ऐसी हरकत करने की गलती नहीं करेंगे। राजीव गांधी के निकटस्थ सांसद व विधायक गण भी समझ रहे हैं कि फिलहाल कांग्रेस के नाम से चुनाव जीतना आसान नहीं है अन्यथा वे कब के इनसे अलग हो चुके होते। देखना तो यही है कि 'फेयरफैक्स' एवं बोफोर्स ने भारतीय राजनीति (खासकर इंका) को इस हद तक झकझोर कर रख दिया है, आगे क्या गुल खिलता है ? सही मायने में कांग्रेस ही नहीं सभी के लिए यह समय बहुत ही नाजुक है। कांग्रेस का विकल्प बनना है तो इससे अच्छा मौका विपक्ष को फिर कभी नहीं मिलेगा। —मुकुल जी, द्वारा डा० डी०डी० कलवार, राजेंद्र नगर, आरा

'माया' ३० अगस्त के अंक की आवरण कथा 'क्या राजीव संकट से उबर पायेंगे ?' सर्वथा प्रासंगिक प्रतीत हुई। अनेक आरोप व विवाद से घिरे प्रधानमंत्री की नेतृत्व कुशलता पर कई प्रश्न चिह्न लगे हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मसलों पर उनका चिंतन व्यावहारिक, दूरदर्शी व संतुलित नहीं लगता, यह उनके अधकचरे ज्ञान को उजागर करता है। उन्हें अब अपने सलाहकारों, मित्रों, शुभचिंतकों के बेकार पचड़े में न पड़कर अपने विवेक से, विचार करके कर्मठ, विश्वसनीय महात्मा गांधी की नीति अपनाकर मार्ग निश्चित करना होगा। अन्यथा नेताओं के निजी स्वार्थों के कारण वे अपने को संकट से निकाल नहीं पायेंगे। —शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, स्टेशन रोड, पो० सक्ती, म०प्र०

खयालात

ज्ञानी जैल सिंह

सुनील गवास्कर

रेखा

इस मारकोस (राजीव गांधी) से छुटकारा पाने के लिए मैं एक्विनो की तरह अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं।

—वी०पी० सिंह, इंडियन एक्सप्रेस से

विश्वनाथ प्रताप सिंह कोई दूध के धुले नहीं हैं। राजीव गांधी के पापों में वह भी सहभागी रहे हैं।

—सिकंदर बख्त

सामंतवाद समाप्त हो गया है, अब तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। **—पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रकाश सिंह, कमलापति त्रिपाठी के बारे में, टेलीग्राफ से।**

अमेठी में तो अब होगा हंगामा...।

—संजय सिंह, इस्तीफे के बाद, टेलीग्राफ से

निलंबन के आदेश से हमें आश्चर्य नहीं हुआ। कांग्रेस पर भ्रष्ट लोगों, पूंजीपतियों और अनुभवहीन व्यक्तियों का कब्जा हो गया है। इससे जाहिर है कि जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायेंगे तो हमें दबाने की कोशिश की जायेगी।

—निलंबन के बाद रामपूजन पटेल

मैं दल के अनुशासन की परवाह नहीं करता। इस बेईमान सरकार को हटाना जरूरी है।

—कांग्रेस-इ से निलंबित होने के बाद रामधन, नवभारत टाइम्स से

ब्रिटिश सरकार—कार्यक्षमता+भ्रष्टाचार=भारत सरकार। **—वी०पी० मेहता, प्रवासी संघ के आयोजक, रांची एक्सप्रेस से**

पिछले दस सालों में महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ी है। खबर निकालने में तो वे मर्दों के कान काटती हैं। मैं चाहता हूं कि हर अंजुमन में कम से कम चालीस प्रतिशत स्त्रियां हों क्योंकि तब मर्द अक्ल से काम लेंगे।

—ज्ञानी जैल सिंह

मैं ऐसा ही अनुभव करता हूं जैसे मेरा पेट अच्छी तरह भरा हुआ है और आप मुझे और खिलाना चाहते हैं—अब मुझे रनों की भूख नहीं है।

—सुनील गावस्कर

अब मैं देश के आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करूंगा।

—पूर्व शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, जनसत्ता से

'सरकार की साख इतनी कम और 'इंडियन एक्सप्रेस' की इतनी ज्यादा है कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा कि ये छापे अखबार को तंग करने के लिए नहीं डाले गये।"

—विनोद मेहता

एक्सप्रेस के अखबारों की धार और तेज और चमकीली होगी।

—रामनाथ गोयनका, जनसत्ता से

मैं चाहती हूं कि दर्शक मुझे इतना चाहें कि हर अभिनेत्री में रेखा को देखें। अगर असली रेखा न मिले तो नकल से काम चलायें, पर रेखा के बिना न रह पायें।

—'रविवार' को दिये इंटरव्यू में रेखा

लगना वामपंथी मुखौटे का!

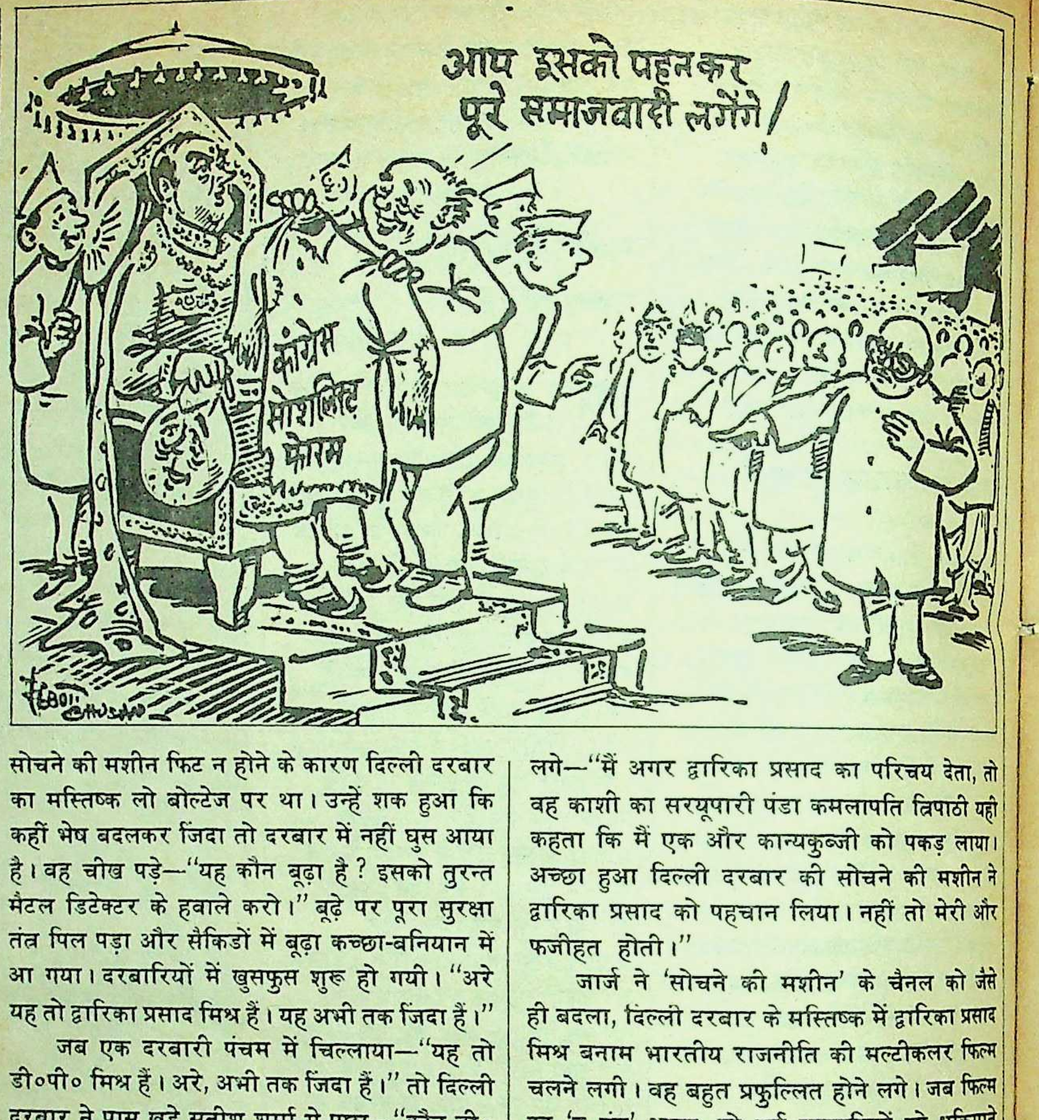
आप इसको पहनकर पूरे समाजवादी लगेंगे!
कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम

दिल्ली दरबार में जब अचानक चेतावनी का सायरन लाल-पीली-नीली बत्तियों के साथ बजा, तो हलचल मच गयी। कंप्यूटरी स्क्रीन पर चूं-चूं...टर्र...टर्र की आवाज में आने लगा—"राजा मांडा के सिर पर बाल उग आये हैं...राजा मांडा के सिर पर बाल उग आये हैं...।" दिल्ली दरबार ने तुरन्त, एक कोने में पड़े घड़े में हाथ डाल कर 'गांधी टोपी' निकाली। टोपी पर फफूंदी लगी हुई थी। उसने दरबार की ओर लपकने के पहले टोपी की फफूंदी को झाड़ने के लिए उस पर औंधे-सीधे तीन-चार हाथ मारे, लेकिन फफूंदी निकलने के बजाय उसमें चिपक गयी। वैसे जार्ज ने लपक कर टोपी पर ब्रुश मारने की कोशिश की, लेकिन सायरन बजने की घबराहट से दिल्ली दरबार ने जार्ज को धकिया दिया—"अब समय नहीं है। राजा मांडा के सिर पर बाल उग आये हैं। मुझे अपने सिंहासन बत्तीसी पर बैठ कर सोचना है कि उसका सिर फिर से कैसे मूंड़ा जाये? जल्दी से मेरी सोचने की मशीन खींचकर लाओ और उसे फिट करो।"

जार्ज उलटे पांव गये और उलटे पांव ही 'सोचने की मशीन' खींचकर ले आये। पीछे से हाथ में नोटबुक और पैंसिल लिये बदहवासी के आलम में दूनी-सखा सुमन दुबे आ गिरे। चेतावनी के सायरन की आवाज और लाल-पीली-नीली बत्तियों की लपक-झपक को देख कर दरबारियों की चूलें हिल गयीं। वे लुढ़कते-ढुलकते दिल्ली दरबार में एकत्र होने लगे। दिल्ली दरबार ने अपनी बत्तीसी निपोर कर जैसे ही सिंहासन बत्तीसी पर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाये, तो पीछे से आवाज आयी—"हे वत्स! रुक जा। सिंहासन बत्तीसी पर चढ़ने से पहले अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत कर?" दिल्ली दरबार ठिठक गया। आवाज में चाणक्यीय खनक थी। दिल्ली दरबार ने सोचा कि बघेल ठाकुर अर्जुन सिंह आवाज बदल कर बोल रहा है। लेकिन मुड़ कर देखा, तो पाया कि—नहीं, यह तो अपना बघेल ठाकुर नहीं है। कोई बूढ़ा है। यह बूढ़ा कौन है? सोचने की मशीन फिट न होने के कारण दिल्ली दरबार का मस्तिष्क लो बोल्टेज पर था। उन्हें शक हुआ कि कहीं भेष बदलकर जिंदा तो दरबार में नहीं घुस आया है। वह चीख पड़े—"यह कौन बूढ़ा है? इसको तुरन्त मैटल डिटेक्टर के हवाले करो।" बूढ़े पर पूरा सुरक्षा तंत्र पिल पड़ा और सैकिडों में बूढ़ा कच्छा-बनियान में आ गया। दरबारियों में खुसफुस शुरू हो गयी। "अरे यह तो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। यह अभी तक जिंदा हैं।"

जब एक दरबारी पंचम में चिल्लाया—"यह तो डी०पी० मिश्र हैं। अरे, अभी तक जिंदा हैं।" तो दिल्ली दरबार ने पास खड़े सतीश शर्मा से पूछा—"कौन डी० पी० मिश्र! यह क्या बेचते हैं?" सतीश शर्मा ने अपने चेहरे पर चश्मा फिट किया, फिर मुंडिया से 'न' हिलाते हुए बुदबुदाया—"अपने फ्लाइंग क्लब का रिटायर्ड चौकीदार डिब्बा प्रसाद मिश्र लग रहा है?" दिल्ली दरबार ने सुमन दुबे से आंख का इशारा करते हुए जब पूछा, तो वह मस्तिष्क पर जोर देते हुए बुदबुदाये "अपने दून स्कूल का चपरासी तो लगता नहीं है। हां, जब मैंने पत्रकारिता में घुसपैठ शुरू की, तो एक बुढ़ऊ पत्रकार से सुना था कि कोई मध्य प्रदेश का डी० पी० मिश्र था, वह अपने जमाने में बहुत चाणक्यीय दांवपेंच, राजनीति में लगाता था। कहीं यह वह तो नहीं है? मगर वह तो कब का 'डिलीट' हो चुका है। लगता है कि खाने-पीने की तंगी से परेशान होकर कुछ मांगने आया है। दे दो चार-छह आने।" इतने में न्यू दिल्ली तिवारी का इशारा पाकर जार्ज ने सिंहासन बत्तीसी के नीचे खड़े दिल्ली दरबार के सोचने की मशीन फिट कर दी। मशीन फिट होते ही दिल्ली दरबार के मस्तिष्क का बोल्टेज बढ़ा, तो उनको खयाल आने लगा—"अरे यह तो पं० द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं।" दूर शीला दीक्षित के कंधे पर लदे उमाशंकर दीक्षित को इशारा करते हुए दिल्ली दरबार ने पूछा—"यह वही द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं।" उमाशंकर दीक्षित ने मुंडिया हिलाते हुए 'हां' की और शीला दीक्षित के कान में फुसफुसाने लगे—"मैं अगर द्वारिका प्रसाद का परिचय देता, तो वह काशी का सरयूपारी पंडा कमलापति त्रिपाठी यही कहता कि मैं एक और कान्यकुब्जी को पकड़ लाया। अच्छा हुआ दिल्ली दरबार की सोचने की मशीन ने द्वारिका प्रसाद को पहचान लिया। नहीं तो मेरी और फजीहत होती।"

जार्ज ने 'सोचने की मशीन' के चैनल को जैसे ही बदला, दिल्ली दरबार के मस्तिष्क में द्वारिका प्रसाद मिश्र बनाम भारतीय राजनीति की मल्टीकलर फिल्म चलने लगी। वह बहुत प्रफुल्लित होने लगे। जब फिल्म का 'द एंड' आया, तो कई दरबारियों को धकियाते हुए वह हाथ जोड़े द्वारिका प्रसाद मिश्र के सामने खड़े थे। दिल्ली दरबार ने मिश्रजी को अपने कंधे का सहारा देते हुए, दरबार में टहलना शुरू कर दिया—"पंडितजी, समस्या यही है कि राजा मांडा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर फिर से बाल उगने लगे हैं। यों तो वह टकला है लेकिन इस बार उसने मुल्क के वामपंथियों से मिल जुल कर अपने सिर के बाल उगाये हैं। हम उसे सी०आई०ए० का आदमी कह कर उसका बेड़ा गरक कर चुके थे, लेकिन उसने जो यह दांव मारा है, उससे मेरे होश फाख्ता हो गये हैं। अब अगर उसे हम के०जी०बी० का आदमी कहते हैं, तो वह मास्को का गोर्बाचोव मुझे मेरी नानी याद दिला देगा। बड़ा संकट आ गया है। आपके पास इस संकट से बचने का कोई फार्मूला हो, तो दीजिए। आपके मेहनताने का पेमेंट हम डालर में कर देंगे। हमारे पास बोफोर्स ही नहीं कई दलालियों का कमीशन आ चुका है।" दिल्ली दरबार ने द्वारिका प्रसाद मिश्र को अपने कंधे से उतार कर एक डनलपी सोफे पर पटक दिया। झटके ने मिश्र की सांस को फुला दिया। जब सांस कंट्रोल में आयी, तो मिश्रजी ने आहिस्ता से तांत्रिकीय अंदाज में अपनी आंखें पलटीं—"कभी भी बिल्ली को खिसियानी स्थिति तक मत घेरो अन्यथा वह मुंह पर पंजे से हमला करेगी ही। राजा मांडा खिसियानी बिल्ली के रूप में बदल चुका है। वह वामपंथी

ज्योति बसु से क्या, माओत्से तुंग को कब्र से निकाल कर उससे लिपटेगा और तुम्हारे लिये संकट पैदा करेगा। जहर-जहर को मारता है। पूंजीवाद को समाजवाद खायेगा, यह दर्शन किताबी है। समाजवाद को समाजवाद ही खा सकता है। तुम अपनी रणनीति बदलो। राजा को उसी अस्त्र से मारने की कोशिश करो, जिससे वह तुम्हें मारने की फिराक में है। आज वह ज्योति बसु के संरक्षण में वामपंथी चोला पहने हुए तुम्हें सी०आई०ए० का एजेंट कहता फिर रहा है। तुम राजा से बड़े वामपंथी बन जाओ। वामपंथी चोले में अगर उसका कद छह फुटा है, तो तुम अपना कद वामपंथी चोले में सात फुटा कर लो। वह बौना दिखेगा।" मिश्रजी की आवाज मंद होने लगी। और वह बुदबुदाने की स्थिति में आ गये। सतीश शर्मा ने लपक कर 'एम्पलीफायर' फिट किया,लेकिन उसके पहले खैनी ओठों में दबाते हुए *विट्ठल गाडगिल* दरबारियों की भीड़ को चीरते आगे *आ गये।*

खैनी की पीक जैसे ही भिच्च से गाडगिल ने मारी, प्रोफेसर जे०एन० रंगा उछल पड़े—"मैं तुम्हारे सोशलिस्ट फोरम की कमर तोड़कर रख दूंगा। मुझे मालूम है कि इस फोरम को तुमने मुझ पर थूकने के लिए फिर से खड़ा किया है।" भांग की तरंग में लड़खड़ाते श्रीपति मिश्र जब तेजी से लपके, तो अमेठी से दर-बदर केदार नाथ सिह से टकरा गये। श्रीपति को धकियाते हुए केदार नाथ सिंह ने कहा, "सुल्तानपुरिये न होते, तो अभी तुमको मजा चखा देता। सुल्तानपुर का लिहाज करके छोड़े देता हूं पंडत।" श्रीपति मिश्र ने केदार नाथ सिह को अनसुना करते हुए रंगा से पूछा, "गाडगिल का समाजवादी थूक आप पर पड़ा तो नहीं। दादा तुम घबराना नहीं। जब मैं यू०पी० का चीफ मिनिस्टर था, तो मैंने एक ही काम किया। वह अपना गोरखपुरिया हरिशंकर तिवारी है, उसे पूरी तरह फिट कर लिया। वह इन सब के भूसा भर देगा।" गाडगिल ने फिर से खैनी की भिच्च मारी और दिल्ली दरबार की ओर लपक लिये, "सर, मैंने वह सोशलिस्ट फोरम फिर से जिन्दा कर लिया है। वह राजा मांडा के वामपंथी मुखौटे को नोच लेगा। आप सोशलिस्ट फोरम की छाती पर खड़े हो जायें, आपका वामपंथी कद राजा मांडा के वामपंथी कद से लम्बा दिखेगा।" गाडगिल दिल्ली दरबार के और करीब बढ़े कि उसके पहले रंगा बीच में आ गये, "यह क्या मजाक हो रहा है। हम स्वतंत्र पार्टी का बोरिया-बिस्तर इसलिए गोलकर इधर आये थे, क्योंकि सारी वे चीजें इधर थीं जो हमारी स्वतंत्र पार्टी में थीं। अब मुझे धोखा दिया जा रहा है। अगर ये लोग सोशलिस्ट फोरम बना रहे हैं, तो मैं नेहरू फोरम बना लूंगा। फिर यह न कहना कि पूरा दिल्ली दरबार फोरमों में बदल गया।" दिल्ली दरबार मुस्कराकर पीछे हट लिये।

दरबार के पीछे हटते ही रंगा को लगा कि दिल्ली दरबार मेरी धमकी में आ गया है। दूसरी ओर गाडगिल को लगा कि अब दिल्ली दरबार लपक कर रंगा पर कोई दांव मारेगा। दरबारियों में बहुत उत्सुकता पैदा हो गयी। जार्ज ने इशारा पाते ही 'सोचने की मशीन' का चैनल फिर पलटा। कुछ देर दिल्ली दरबार बुत बने रहे। वह अपनी मशीन के जरिये सोच रहे थे। सोचने के बाद उन्होंने फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान लपेटी—"मूर्खों, क्यों आपस में लड़ते हो। मेरी मशीन सोच कर यह बता रही है कि हम लोग न तो वामपंथी हैं और न दक्षिणपंथी और न ही कबीरपंथी। हम लोग हैं निजीपंथी। निज को बचाने के लिए कभी हमको दक्षिणपंथी मुखौटा लगाना होता है, कभी वामपंथी। अब हम लोगों को राजा मांडा के वामपंथी मुखौटे को टक्कर देने के लिए वामपंथी मुखौटे की जरूरत है। हम उसे लगाये लेते हैं। इसमें इतना बावेला करने की क्या जरूरत। काम निकल जायेगा, उसे फिर कोने में रखे घड़े में डाल देंगे। उस घड़े में जो वह कोने में रखा ऊंघ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने उस घड़े से यह फफूंदी लगी गांधी टोपी निकाली थी।" सारे दरबारी मुंह बाये दिल्ली दरबार का राजनीतिक दर्शन सुने जा रहे थे। रंगा और गाडगिल अपने-अपने निजी भाव से एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। एक दूसरे की आत्माएं परमात्माएं हुई जा रही थीं। पीछे से गोपी अरोड़ा भागे-भागे आये, तो किसी दरबारी ने अपना ट्रांजिस्टर मगन होकर खोल दिया, जिस पर गाना आ रहा था—"मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून इंगलिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल..."

> **"मुझे वामपंथी मुखौटा राजा मांडा को उसकी नानी याद दिलाने के लिए पहनना पड़ेगा। तुम मेरी एक वामपंथी स्पीच तैयार करो। मैं उसे सोशलिस्ट फोरम के मंच से पढ़कर राजा मांडा की नहीं, बल्कि ज्योति बसु की भी ऐसी-तैसी कर दूंगा।"**

ट्रांजिस्टर पर गाने की आवाज सुनकर दिल्ली दरबार ने इधर-उधर गरदन हिलायी और सोचने की मशीन का चोंगा ठीक किया। जार्ज ने इशारा किया कि यह गाना सोचने की मशीन से नहीं उधर दरबारियों के किसी ट्रांजिस्टर से आ रहा है। दिल्ली दरबार ने तुरन्त अजित कुमार पांजा को आंख दिखायी—"यह क्या तुम्हारा रेडियो चौबिसों घंटे गाना ही बजाता रहता है।" पांजा रेडियो स्टेशन की बत्ती जब तक गुल करायें, उसके पहले सुमन दुबे लपक लिये—"दिल्ली दरबार मुल्क को २१वीं शताब्दी में दिल के जरिये नहीं, मशीन के जरिये ले जा रहे हैं। आप लोग दिल हैं हिन्दुस्तानी का मोह अभी तक नहीं छोड़ पाये हैं। फौरन बंद करिये ट्रांजिस्टर।" दरबारी ने घबरा कर ट्रांजिस्टर और दिल दोनों झट से बंद कर दिये।

गोपी अरोड़ा ने मौका पाकर दिल्ली दरबार के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया, "सूखे से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध कर लिये हैं। आपको सूखे का नंगा अवलोकन कराने के लिए दौरे के सारे कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। सूखाश्री की उपाधि के लिए काफी सिफारिशें आयी हैं। उनको भी इस फाइल में आपके देखने के लिए रख दिया है। यों तो पिछले दिनों पानी बरस जाने से सूखे का प्रभाव कम हो चला है, लेकिन मैंने आपके दरबारी कागजों में उसके प्रभाव को और ज्यादा दिखा दिया...।" दिल्ली दरबार ने गोपी अरोड़ा को धकिया दिया—"अरे सूखा, सूखा क्या रट रहा है। वी०पी० सिंह सूखे से हट कर वामपंथ पर चला गया है। सूखा छोड़ो, वामपंथ लाओ। तू तो काफी पहले से मास्कोआइड मुखौटा लगाये घूम रहा है। उस सोफे पर खर्राटें भर रहे बूढ़े को जगा कर पूछो कि उसकी इस बारे में क्या राय है। यह बुड्ढा हमारा पुराना पुरोहित है।" गोपी द्वारिका प्रसाद मिश्र के पास पहुंचे, तो वह बुदबुदा रहे थे, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि दिल्ली दरबार का 'एम्प्लीफायर' भी पकड़ नहीं पा रहा था। गोपी अरोड़ा का इशारा पाकर एक नकाबपोश ने आकर मिश्रजी को 'स्टार ट्रेक इंजेक्शन' लगाया, तो बूढ़ा आंख खोलकर बैठ गया।

गोपी अरोड़ा जब पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र से बतियाकर दिल्ली दरबार के पास पहुंचे, तो वह 'सोचने की मशीन' का चोंगा उतार कर ठस हो चुका था। गोपी ने यह नहीं देखा कि दिल्ली दरबार का मस्तिष्क लो वोल्टेज पर आ गया है। उन्होंने दिल्ली दरबार को बताना शुरू किया, "पंडत तो कई दशक पहले सठिया चुका है। कोई काम की बात तो बता नहीं पाया। इसीलिए मैंने उसे कुछ देकर विदा कर दिया। मैं सोशलिस्ट फोरम के लिए आपका भाषण तैयार किये देता हूं। सोशलिस्ट फोरम में आपका भाषण इतने धमाके का होना चाहिए कि ज्योति बसु और नम्बूदरीपाद दोनों को नानी याद आ...।" दिल्ली दरबार ने बीच में ही बात काट दी, "कौन सा सोशलिस्ट फोरम! कैसा भाषण! कौन है यह ज्योति बसु और नम्बूदरीपाद! मैं क्यों भाषण दूं।" पूरा दिल्ली दरबार सकते में आ गया। गोपी अरोड़ा ने तुरन्त जार्ज को इशारा किया। जार्ज ने फुरती से 'सोचने की मशीन' का चोंगा दिल्ली दरबार के फिट करके तड़ातड़ चैनल बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही सैकिडों में दिल्ली दरबार अपने पूरे फार्म पर आ गया "हां, गोपी। मुझे वामपंथी मुखौटा राजा मांडा को उसकी नानी याद दिलाने के लिए पहनना पड़ेगा। तुम मेरी एक वामपंथी स्पीच तैयार करो। मैं उसे सोशलिस्ट फोरम के मंच से पढ़कर राजा मांडा की नहीं, बल्कि ज्योति बसु की भी ऐसी नैसी कर दूंगा।"

दिल्ली दरबार की उद्घोषणा को सुनकर प्रोफेसर रंगा ने लपक कर गाडगिल का कालर पकड़ लिया। केदार नाथ सिह गाडगिल को छुड़ाने के लिए लपके कि पीछे से श्रीपति मिश्र ने भांग की तरंग में दिल्ली दरबार से उत्तेजित होकर कुछ पूछना शुरू कर दिया। पास खड़े पी० शिवशंकर ने श्रीपति मिश्र की गरदन दबोच ली। इसी समय सुरक्षा को जब खतरा पैदा होने लगा, तो ब्लैक कैट ने मिऊमिऊ करके श्रीपति मिश्र को दबोच लिया। दरबार में हंगामा मच गया। फिर उसी दरबारी का ट्रांजिस्टर खुल गया—सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी, अभी आप फिल्म श्री ४२० का गाना सुन रहे थे।

—दरबारी लाल

अनजाने सांसद

राजधानी के हवाई अड्डों पर कुख्यात आतंकवादियों की तस्वीरों के पोस्टर चिपके हुए हैं, किंतु पिछले दिनों हुई दो घटनाओं के बाद, तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को यह लगने लगा है कि अब ज्यादा जरूरी यह है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की तस्वीरों का भी एक बड़ा पोस्टर प्रवेश द्वार पर चिपका दिया जाये, ताकि इन अतिविशिष्ट व्यक्तियों को न पहचान पाने से होने वाली 'दुर्घटनाओं' से बचा जा सके।

कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री सरोज खापर्डे को न पहचान पाने के 'अपराध' की सजा एक अज्ञानी सुरक्षाकर्मी भुगत चुका है। वी०आई०पी० लाउंज में घुस रही सरोजजी के खुद बताने के बावजूद कि वह मंत्री हैं, उस नासमझ को शायद विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे लोग भी मंत्री हो सकते हैं और उसने बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किये केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री से अपना परिचय पत्र दिखाने को कहा। फिर क्या था, गुस्से में थरथराती सरोजजी की नाराजगी पूरे हंगामे के साथ बरपी। उस अदने से सुरक्षाकर्मी से लेकर उच्च-अधिकारी तक कई दिन हाथ जोड़े कांपते रहे।

लेकिन केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को हर व्यक्ति पहचाने ही, ऐसा अभी तक कोई नियम नहीं बना है। इस घटना के कुछ दिनों बाद २६ अगस्त को पालम हवाई अड्डे पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्तामणि पाणिग्रही के साथ भी 'पहचान-का संकट' खड़ा हो गया। किंतु इस बार उन्हें न पहचानने की गलती करनेवाला कोई अदना सुरक्षाकर्मी नहीं, बल्कि एक हिन्दी पाक्षिक के संपादक थे। दिल्ली से रायपुर जा रहे संपादक महोदय प्रवेश द्वार पर सामान्य सुरक्षा जांच के लिए बनी यात्रियों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े थे। उसी पंक्ति में दो सांसद सुभाष यादव व दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले कि संपादक महोदय अन्दर बढ़ें, एक तरफ से तेजी से आ रहे धोती-कुर्ता धारी चिंतामणि पाणिग्रही पूरी पंक्ति को पारकर अंदर जाने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने तो इस बार मंत्रीजी से परिचय पूछने का 'दुस्साहस' नहीं किया पर संपादक महोदय को यह नागवार गुजरा। उन्होंने बिना लाइन के उनसे पहले अन्दर जाते नेताजी को वहीं रोकते हुए उनका परिचय जानना चाहा। नेताजी ने जवाब दिया, "मैं मंत्री हूं।" फिर क्या था संपादक जी का पारा सातवें आसमान पर था। इधर संपादकजी मंत्री महोदय द्वारा पंक्ति तोड़कर अन्दर जाने पर बरस रहे थे, उधर सुरक्षाकर्मी मुस्करा रहे थे कि जब राजनीतिक पाक्षिक के संपादक तक मंत्रियों को नहीं पहचानते, तो हम अदने कर्मचारियों से कोई यह आशा क्यों करे?

सुख से वंचित सांसद

बिहार के एक जाने-माने (दरअसल कुख्यात) सांसद जब से कुछ समय पहले स्वीडन की यात्रा से लौटे हैं, उदास हैं। वह एक संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे, जो अन्य यूरोपीय देशों के साथ-साथ स्वीडन भी गया था (बोफोर्स के संबंध में नहीं)।

हुआ यह कि अपने सांसद काफी रंगीन तबीयत के आदमी हैं। यों भी उनका नाम या बदनामी उनकी राजनीति पर नहीं, तस्करी जैसे पवित्र कार्यों में उनकी शिरकत पर टिकी है। स्वीडन, जैसा कि सब जानते हैं, यौन मामलों में अपनी उदारता के लिए विख्यात है। इस विशद विषय के हर पहलू पर रसिकों की रुचि और मांगों को तृप्त करने के लिए स्टाकहोम में एक विशाल बाजार है।

सो अपने सांसद महोदय ने कई घंटों के श्रम के बाद पूरा बाजार घूमकर आधा दर्जन से अधिक चुनिंदा ब्लू फिल्में खरीदीं और मुदित भाव से होटल के अपने कमरे में करीने से रख दीं, किंतु होटल का एक बैरा शायद उनसे अधिक रसिक और चुस्त था। फिल्में रखकर सांसद किसी काम से बाहर गये। लौटे तो फिल्में नदारद। अब उस समय न तो इतना समय था, उनके पास कि फिर बाजार जाते, न ही एक अच्छी-खासी राशि दोबारा खर्च करने का साहस। चोरी की रिपोर्ट भी वह किस मुंह से करते सो, खाली हाथ लौटे और आज भी उदास हैं।

अर्जुन-केसरी मिलन

दो पुराने शत्रुओं में अब मेल हो गया है। जहां पहले कूटोक्तियों और निंदा की शिष्ट-अशिष्ट धाराएं बहती थीं, अब सहसा आदरसूचक अभिवादन और प्रशंसा-भरा मौन बह रहा है। दोनों हस्तियां हैं, अर्जुन सिंह और सीताराम केसरी।

केसरीजी को शिकायत थी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते हुए अर्जुन सिंह ने उनके पर काटने की भरपूर और लगातार कोशिशें की थीं। अर्जुन सिंह को वह अरुण नेहरू के बाद अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। अर्जुन सिंह को मलाल था कि केसरी ने अपनी राजनीति में उनकी शैली और हितों का ध्यान नहीं रखा, किंतु साझी मुसीबत शत्रुओं को मित्र बना देती हैं। पिछले कई महीने से कांग्रेस में चल रही उखाड़-पछाड़ में दोनों महारथियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। केसरी को राज्यसभा का टिकट एक बार फिर नहीं दिया गया और अर्जुन सिंह को कांग्रेस उपाध्यक्ष के शक्तिशाली पद से हटा दिया गया था। दोनों के चेहरों पर चमक लौट आयी है, इस समझ के साथ कि आपस में शीत युद्ध से दोनों को हानि है और मिलकर चलने से लाभ।

गोपी कृष्ण की गोपनीय छुट्टियां

सितंबर के प्रथम सप्ताह में, जब राजीव गांधी और उनकी सरकार सूखा, बाढ़, वी०पी० सिंह, बोफोर्स और संजय सिंह से जूझ रही थी, राजनीतिक क्षेत्रों में एक प्रश्न पूछा जा रहा था—इस समय गोपी अरोड़ा एक हफ्ते की छुट्टी कैसे मना रहे हैं?

जब से राजीव गांधी ने अपने दून स्कूली, मैनेजमेंट विशेषज्ञ मित्र-सलाहकारों को अपने से कुछ दूर किया है, उनके सचिव गोपी कृष्ण अरोड़ा उनके सबसे विश्वस्त और शक्तिशाली सलाहकार-सहायक के रूप में उभर हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी अपुष्ट चर्चायें भी चली थीं कि कुछ समय से उनके महत्व में कुछ कमी आयी है। अफवाह तो यह भी थी कि गोपी स्वयं इस कांटों के ताज को उतारकर उत्तर प्रदेश के मुख्य-सचिव जैसी कम सिरदर्द वाली जगह जाना चाहते हैं।

बहरहाल, जानकार क्षेत्रों में पूछताछ से पता चला कि अरोड़ा दिल्ली में ही हैं, स्वस्थ हैं और निकट भविष्य में उनके हटने की संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं, किंतु उनकी इस सप्ताह-भर लंबी छुट्टी का कारण सबके लिए अज्ञात था। क्या वह प्रधानमंत्री के लिए किसी अति-महत्वपूर्ण गुप्त प्रोजेक्ट पर नित्य-प्रति की अनुत्पादक व्यस्तता से अलग जुटे हुए थे? ■

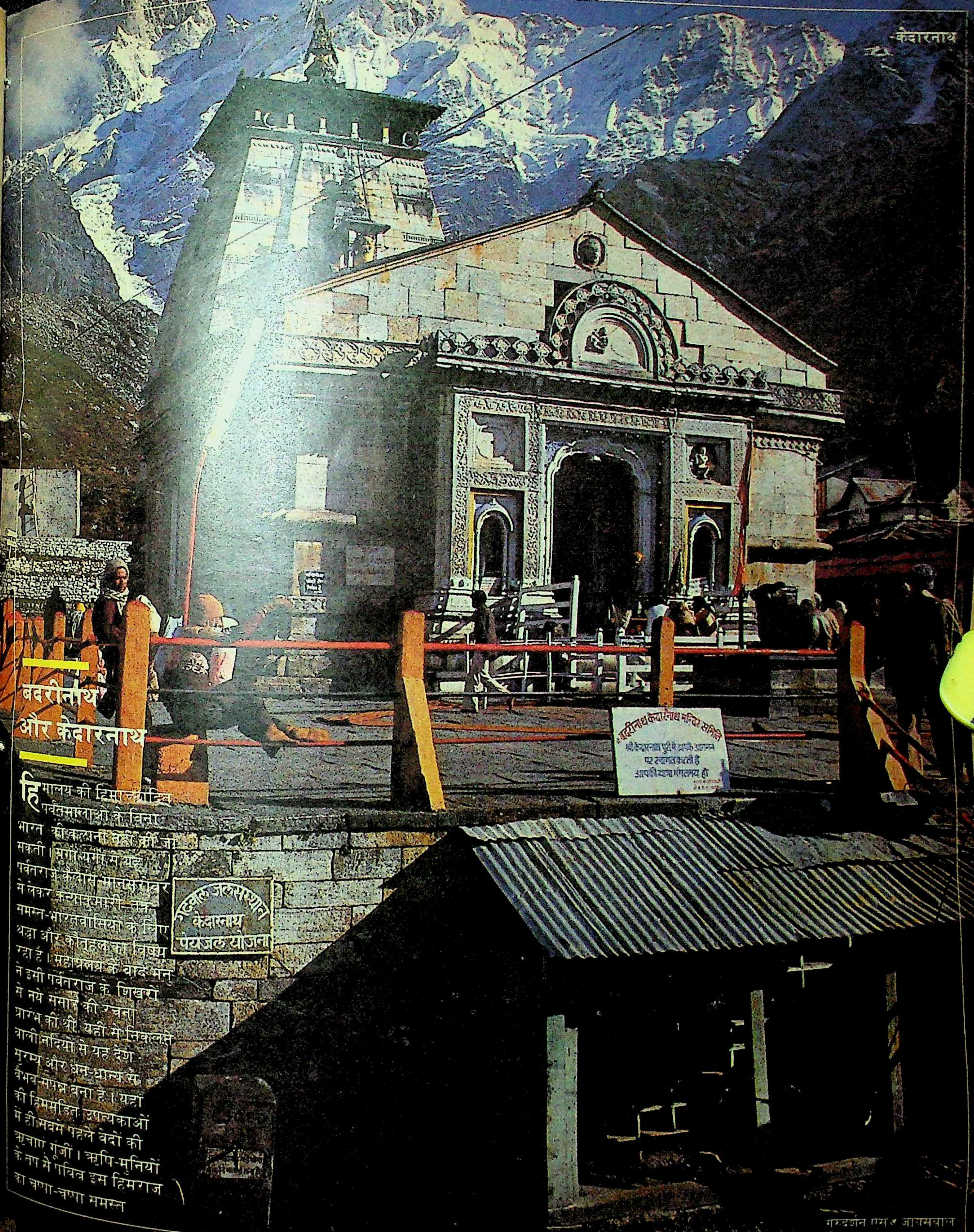
बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति
गढ़वाल जलसंस्थान
केदारनाथ
पेयजल योजना

केदारनाथ

बदरीनाथ और केदारनाथ

हिमालय की हिमाच्छादित पर्वतमालाओं के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। युगों-युगों से यह पर्वतराज कैलास मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्त भारतवासियों के लिए श्रद्धा और कौतूहल का विषय रहा है। महाप्रलय के बाद मनु ने इसी पर्वतराज के शिखरों से नये संसार की रचना प्रारंभ की थी। यहीं से निकलने वाली नदियों से यह देश सुरम्य और धन-धान्य से वैभव-संपन्न बना है। यहां की हिममंडित उपत्यकाओं में ही सबसे पहले वेदों की ऋचाएं गूंजीं। ऋषि-मुनियों के तप से पवित्र इस हिमराज का चप्पा-चप्पा समस्त

गुरुदर्शन एस० जायसवाल

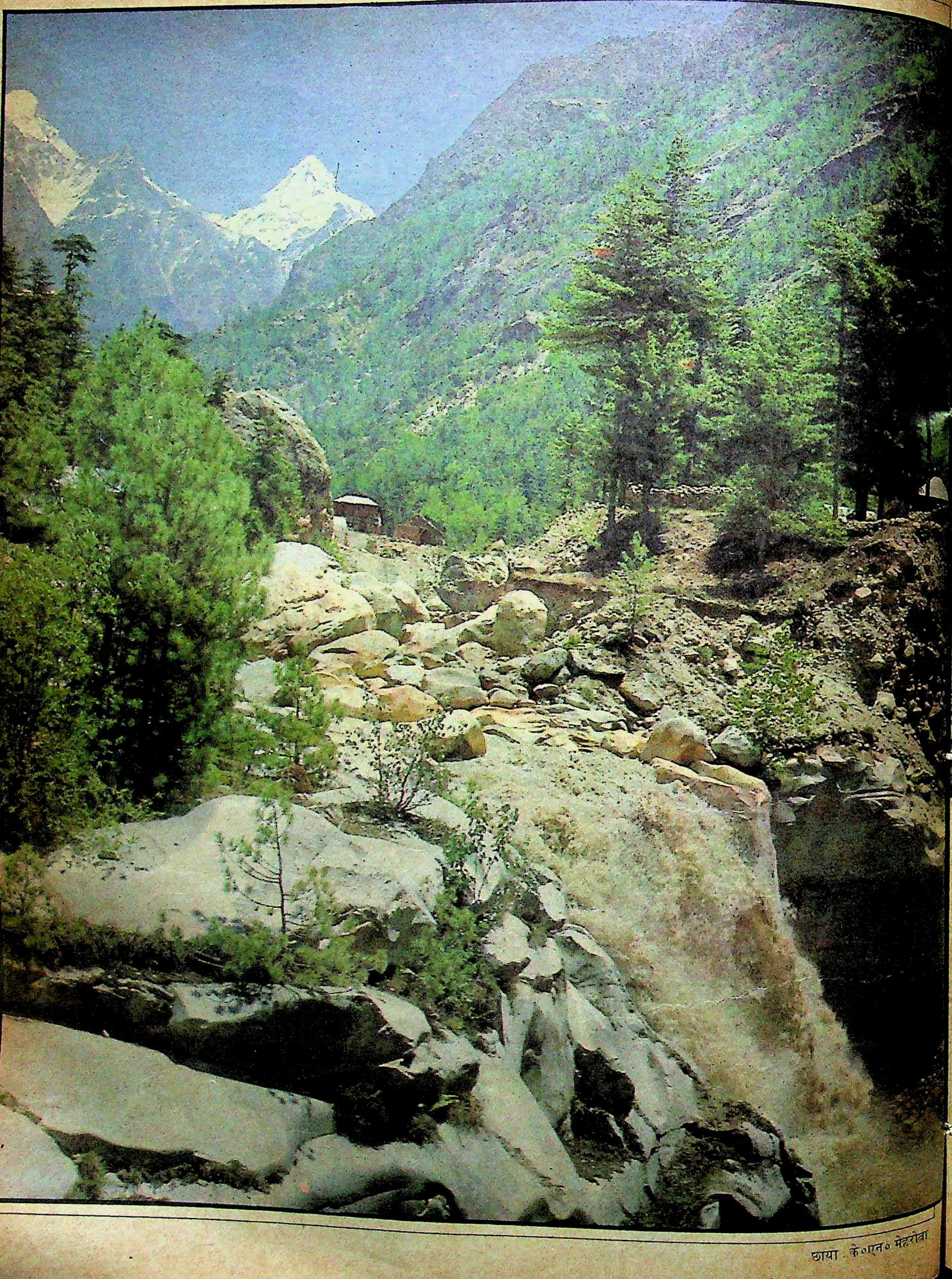

छाया : के०एन० मेहरोत्रा

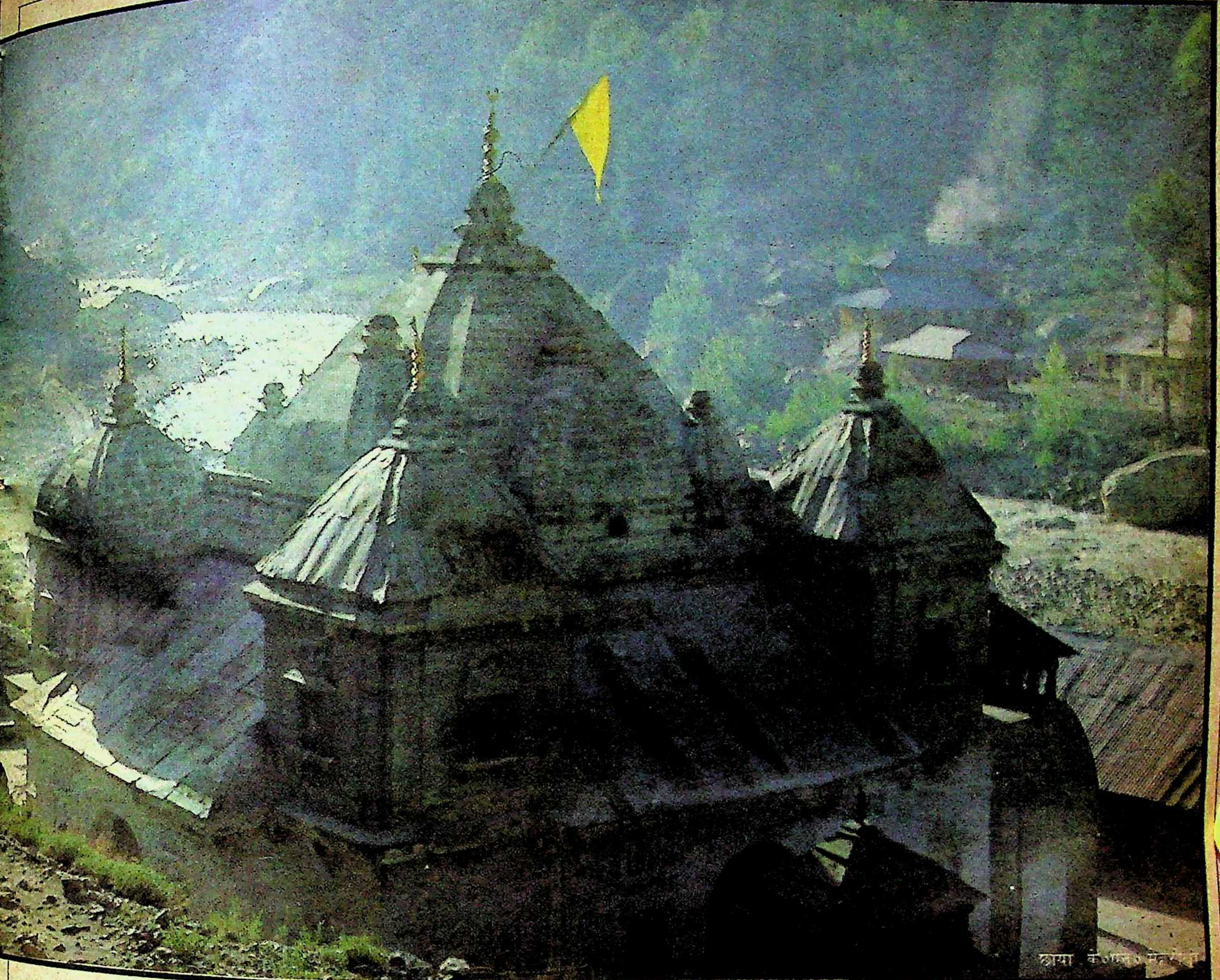

छाया : के.एम. मेहरोत्रा

भारतवासियों की दृष्टि में देवस्थल है। प्राकृतिक बाधाओं की परवाह न करते हुए इस देश के प्रतापी और यशस्वी पूर्वजों ने हिममंडित शिखरों को लांघा, पुण्य नदियों के उद्‌गम स्थलों तक गये और स्थान-स्थान पर मंदिरों और मठों की स्थापना की।

कश्मीर घाटी से लेकर अरुणाचल तक विस्तीर्ण हिमालय की पर्वतमालाओं में इतने तीर्थस्थल हैं कि गणना करना असंभव है। प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान अबुल फजल ने सोलहवीं शताब्दी में लिखा था कि अकेले कश्मीर घाटी में ही शिव के ४५, विष्णु के ६४, ब्रह्मा के तीन और शक्ति दुर्गा के २२ पावन मंदिर हैं। इनकी स्थापत्यकला को देखकर आज भी आश्चर्य होता है कि इतने दुर्गम क्षेत्रों में इतने भव्य निर्माण आखिर कैसे संभव हुए?

हिमालय क्षेत्र के तीर्थ स्थलों की यात्रा वर्षा एवं शीत ऋतु को छोड़कर अर्थात अप्रैल मई, जून, सितंबर एव अक्तूबर मास में की जाती है। जो लोग बदरीनाथ-केदारनाथ आदि उत्तराखण्ड के तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, वे अपनी यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ करते हैं, और यमुना एवं गंगा के उद्‌गम स्थलों—यमुनोत्तरी गंगोत्तरी होते हुए केदारनाथ-बदरीनाथ और नंदादेवी के दर्शन करके उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा संपन्न करते हैं। बदरीनाथ हरिद्वार से २९० किलोमीटर दूर है और केदारनाथ बदरीनाथ से ११७ किलोमीटर।

हरिद्वार से तीर्थयात्री ऋषिकेश पहुंचते हैं और यहीं से हिमालय के पर्वतों की चढायी प्रारंभ हो जाती है। जहां से तीर्थयात्री टिहरी होते हुए हनुमानचट्टी पहुंचते हैं, यहां से यमुनोत्तरी केवल १२ किलोमीटर दूर है। यमुना मंदिर में यमुना मैया के दर्शन करके तीर्थयात्री गंगोत्तरी की ओर बढ़ते हैं और उत्तर काशी, गुप्त प्रयाग, हरि प्रयाग होते हुए भैरव घाटी पहुंचते हैं। यहां से १० किलोमीटर पर गंगोत्तरी है और गंगोत्तरी से २७ किलोमीटर आगे समुद्र तल से १०००२० फुट की ऊंचाई पर गंगाजी का उद्‌गम स्थल गोमुख स्थित है। यहां गंगाजी केवल ४४ फुट चौड़ी हैं।

गंगोत्तरी से भल्लाचट्टी-भैरोचट्टी होते हुए तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचते हैं। केदारनाथ भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां कोई निर्मित मूर्ति नहीं है, एक बहुत विशाल त्रिकोण पर्वत खण्ड है। तीर्थयात्री यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी से एकत्र जल केदारनाथ में चढ़ाते हैं।

केदारनाथ से तीर्थयात्री बदरीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। जोशी मठ तक अब वाहन भी उपलब्ध हैं। जहां से विष्णु प्रयाग और पाण्डुकेश्वर होते हुए तीर्थयात्री बदरीनाथ धाम पहुंचते हैं।

केदारनाथ भगवान शिव का मंदिर है, तो बदरीनाथ भगवान विष्णु के सहस्रनाम-रूपों में से एक नाम-रूप है। भव्य मंदिर में शालिग्राम शिला पर भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति प्रतिष्ठित है। माथे पर एक विशाल रत्न, शरीर पर स्वर्णाभूषण, सिर पर सोने का छत्र

इस मूर्ति को भव्य बना देते हैं। साल में छह मास तक यह मंदिर बर्फ के कारण बंद रहता है। मंदिर के कपाट बंद करते समय प्रवेश द्वार पर एक लैंप जला दिया जाता है जो मंदिर के पुन: खुलने तक जलता रहता है। इस अवधि में भगवान बदरीनाथ की प्रतिनिधि मूर्ति की जोशी मठ में पूजा होती है।

उत्तराखण्ड के इन तीर्थों की यात्रा आज वाहन और सड़क सुविधा होने के कारण बड़ी सरल हो गयी है, लेकिन भारतवासी युगों-युगों से इन तीर्थस्थलों की यात्रा करते रहे हैं। दक्षिण भारत के तीर्थयात्री रामेश्वरम से जल लेकर केदारनाथ धाम में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो उत्तर भारत के तीर्थयात्री गोमुख और यमुनोत्तरी से जल लेकर धुर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंचते हैं और सेतुबंध पर स्थित शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। पवित्र-धामों की तीर्थयात्रा पर निकला भारतवासी अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर भी यह अनुभव नहीं कर पाता कि वह घर से दूर है। अलग-अलग दिखायी देते हुए भी इन पुण्य स्थलों के प्रति सभी के हृदयों में एक जैसा ही भाव रहता है और यही वह भाव है जो अनेक विविधताओं के बावजूद भारतवासियों को युगों-युगों से एक सूत्र में जोड़े हुए है।

बदरीनाथ मंदिर का गेट

गोमुख [illegible]

विकृत मुख

तेल के धन से अमीर बने खाड़ी के देशों के अमीरजादों के विकृत यौन मुख के लिए गरीब मुल्कों से बहला-फुसलाकर, खरीद-कर या अपहरण करके छोटी उम्र के लड़के-लड़कियों को खाड़ी के देशों में बेच दिया जाता रहा है। यह सिलसिला बहुत अर्से से चल रहा है। भारत में भी अनेक ऐसे मामले सामने आये हैं, जिनमें खाड़ी के देशों के अमीर अरबों ने दक्षिण भारत की गरीब लड़कियों से विवाह का नाटक किया, लेकिन खाड़ी के देशों में पहुंचते ही ये लड़कियां उनकी विकृत यौन संतुष्टि का साधन बनीं और वेश्याओं से बदतर जिंदगी जीने तथा इस हाथ से उस हाथ बिकने के लिए मजबूर हो गयीं। हाल ही में पाकिस्तान पुलिस द्वारा करांची के एक होटल से १० से १३ साल की उम्र के २३ बच्चों को एक दलाल से मुक्त कराने पर जो दर्दनाक कहानी सामने आयी है, वह खाड़ी के अमीरों की एक और विकृत मनोवृत्ति का परदाफाश करती है।

खाड़ी के इन अमीरजादों को एक शौक है 'ऊंट की दौड़' का। अपने ऊंट को इस दौड़ में विजयी बनाने के लिए खाड़ी के प्रायः सभी अमीर एक वीभत्स तरीका अपनाते हैं। इसके लिए वे छोटी उम्र के लड़कों को खरीद लेते हैं। इन्हें 'जोकीज' कहा जाता है। ऊंट दौड़ शुरू होने से पहले हर ऊंट की पीठ पर ऐसे लड़के को बांध दिया जाता है। दौड़ शुरू होने का संकेत होते ही ऊंट को चाबुक मारकर दौड़ाया जाता है और उसकी पीठ के पिछले भाग से बंधा लड़का भय और पीड़ा से चीखता रहता है और इस चीख से घबड़ाकर ऊंट भी तेजी से दौड़ता है। ऐसा माना जाता है कि लड़का जितनी जोर से चीखेगा, ऊंट उतना ही तेज दौड़ेगा। ऊंट दौड़ के पूर्वाभ्यास में भी इन जोकीज लड़कों को ऊंटों से बांधा जाता है। हर ऊंट दौड़ में काफी लड़के बुरी तरह घायल होते हैं और अनेक मर भी जाते हैं।

इन अमीरों के दलाल दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों से बच्चों का अपहरण करके उन्हें खाड़ी के देशों में ले जाते हैं। भारत में खोया कोई बच्चा यदि नहीं मिलता, तो यह भी संभव है कि वह 'जोकीज़' बनने के लिए खाड़ी के देशों के इन अमीरों को बेच दिया गया हो।

सुअर बाला

ऐसे दुर्लभ प्रसंग सामने आते रहे हैं कि भेड़िया किसी शिशु को उठाकर ले गया और भेड़िया परिवार के साथ पलकर जब वह बड़ा हुआ, तो उसका खान-पान, रहन-सहन बोली सब कुछ भेड़ियों जैसी हो गयी। करीब दो दशक पहले उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में दो लड़कियां एक भेड़िये की मांद में मिली थीं। वे कीड़े-मकोड़े, कच्चा मांस आदि खाना पसंद करती थीं। मनोचिकित्सकों ने उन्हें मनुष्य बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे। भेड़ियों की परवरिश में वे ११-१२ साल जिंदा रहीं, लेकिन मनुष्यों की देखरेख में वे दो साल में ही चल बसीं।

बहुत अर्से बाद ऐसी ही एक खबर चीन से आयी है। यहां के लियोनिंग प्रांत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ताइयान गांव में एक ऐसी १३ वर्षीय लड़की मिली है, जो सुअरों के बीच पलकर बड़ी हुई और लड़की का शरीर होते हुए भी खान-पान, और स्वभाव में वह पूरी तरह सुअर बन चुकी है। वह सुअर का दूध पीती है, सुअर की तरह झुककर दोनों हाथों और पैरों से चलती है। चीन के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और अन-शान इंस्टीट्यूट आफ साइकोमेट्री में वांग झियांग नामक इस सुअर बाला पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस लड़की को सेक्सबोध नहीं है। वह न तो चीनी भाषा जानती-समझती है और न ही किसी को पहचानती है। रंगों का उसे ज्ञान नहीं है। भूख और दर्द के सिवा कोई अन्य संवेग उसमें नहीं है।

हुआ यह था कि इस लड़की के पिता गूंगे और बहरे थे और मां मानसिक रोगी। वे इस बच्ची की देखभाल नहीं कर सकते थे और उन्हें इस बात की कोई समझ भी नहीं थी कि आखिर वह इस बच्ची का करें क्या? उन्होंने उसे पालतू सुअरों के बाड़े में रख दिया, जहां सुअरों ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला। चूंकि उनका घर गांव से दूर एकांत स्थान पर था और कोई उनके घर आता-जाता भी नहीं था, इसलिए सुअरों के साथ पलती उस बच्ची की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जब पता चला तो वह १३ साल की हो चुकी थी। चीनी विशेषज्ञ उसे मनुष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होने का उन्हें पूरा भरोसा है।

बिकाऊ जलमहल

इंग्लैण्ड की एक फर्म 'पीटर इनसेल्स' पानी पर तैरते एक आलीशान महल के खरीदार की तलाश में है। इसकी कीमत तीन करोड़ पचास लाख डालर (करीब ४२ करोड़ रुपए) लग चुकी है। तेरह हजार टन भार का 'नवीला' नामक यह विशाल जल महल पोत फ्रांस के एक समुद्र तटीय पर्यटन स्थल पर लंगर डाले खड़ा है। वैसे तो विश्व के कुछ इने-गिने लोगों को ही इस जलमहल में जाने का सौभाग्य मिला है, फिर भी यदि आपकी जेब में ४२ करोड़ रुपए हैं, तो आप खरीदने से पहले इसका मुआयना कर सकते हैं।

इस जलमहल की भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए तो इसके मालिक का नाम जान लेना ही पर्याप्त है—वह हैं, सऊदी अरब के हथियारों के करोड़पति व्यापारी अदनान खशोगी। कभी वह ईरान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई करके अमरीकी राष्ट्रपति रीगन के गले का फंदा बन जाने के लिए चर्चित होते हैं, तो कभी अपने आध्यात्मिक गुरू चंद्रास्वामी के कारण। पिछले दिनों उन्होंने लीबिया के मूडी राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी से अपनी बेटी के विवाह की घोषणा की और साथ ही अपने विशाल जलमहल को बेचने की। इस तैरते महल में वह सब कुछ है जो एक आलीशान महल में होता है। भव्य रंगीन दावतों की व्यवस्था, स्वीमिंग पूल, विशेष मेहमानों के लिए सजे-धजे ११ विशाल कक्ष, हेलीपेड आदि। देखना है, कौन खुशकिस्मत इस महल का मालिक बनता है। वैसे भारत में ही अनेक लोग ऐसे हैं जो यह महल खरीद सकते हैं, लेकिन बोफोर्स कांड के उछलने के कारण ऐसा महल खरीदने की हैसियत रखनेवाले कालेधन के स्वामी भारतीय शायद चुपचाप बैठ गये हैं।

संयोजन : विनोद मिश्र

अमेठी

बिना संजय सिंह के राजीव गांधी

इस समय राजीव गांधी की छवि, विश्वसनीयता और राजनीतिक कुशलता दांव पर लगी हुई है। विपक्ष और विद्रोही कांग्रेसी उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता के उत्स—अमेठी—का क्या हाल है ? संजय सिंह की बगावत के बाद क्या अमेठी में भी उनकी लोकप्रियता क्षीण हो रही है ? क्या उनका तीन दिवसीय (१०, ११ और १२ अगस्त) दौरा इसी चिंता का परिचायक था ?

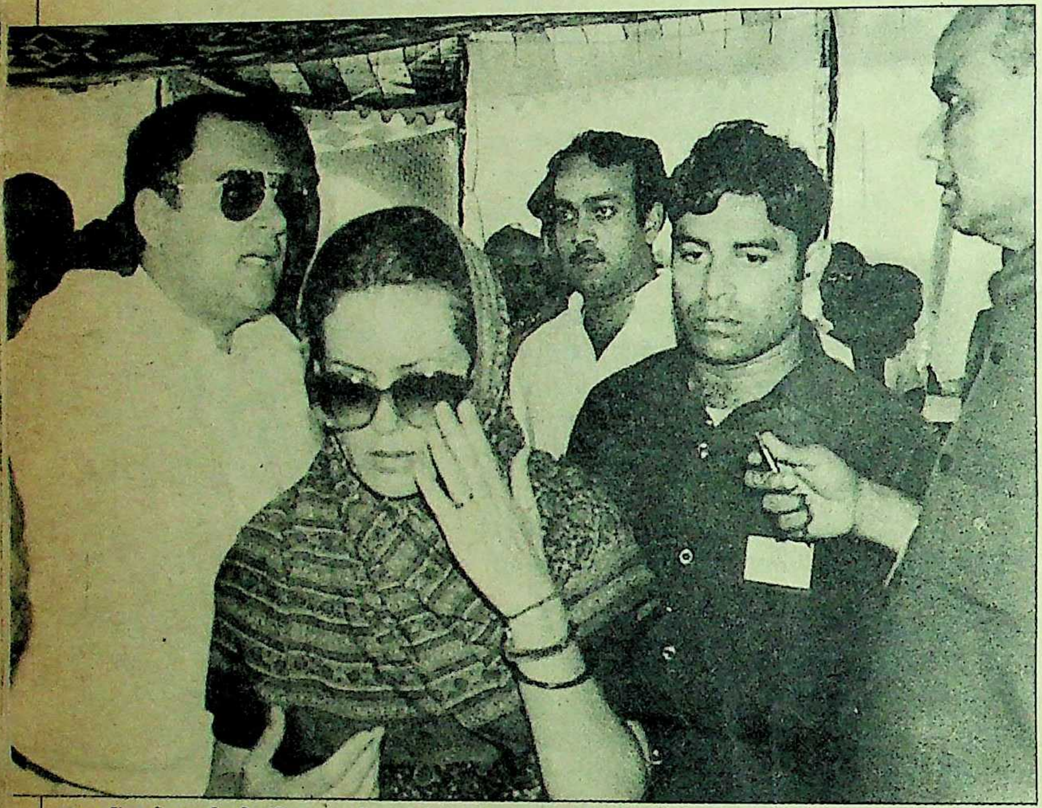

संजय सिह के समर्थन से वंचित : राजीव, सोनिया के साथ संजय सिह छाया : स्वदेश कुमार

वर्ष १९८४ के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी को रिकार्ड मतों से विजयी बनाने की व्यूह रचना करनेवाले अमेठी के राजकुमार संजय सिह जब तक राजीव गांधी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिह के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तब तक उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी के लिए वी०पी० सिह ही सबसे बड़ा खतरा समझे जाते थे, लेकिन मंत्रिमंडल छोड़ने और कांग्रेस-इ से निष्कासित हो जाने के बाद संजय सिह (और उनके पिता अमेठी के भूतपूर्व राजा रणंजय सिह) जिस प्रकार राजीव गांधी को अमेठी के आगामी चुनावों में देख लेने की चुनौती दे रहे हैं, उससे राजनीतिज्ञों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री के लिए वी०पी० सिह के बजाय एक विधायक संजय सिह की बगावत कहीं अधिक घातक साबित हो सकती है। अमेठी पूरे हिंदुस्तान का एक निराला चुनाव क्षेत्र है। सिर्फ दस वर्ष पूर्व तक घोर दरिद्रता का दृश्य उपस्थित करनेवाला यह इलाका श्रीमती गांधी परिवार का दुलारा बनने के बाद बड़ी तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ा—करोड़ों रुपए इस क्षेत्र में लगा देने के बावजूद यह गांधी परिवार की कभी बपौती नहीं रहा। यहां के मतदाता हवा के रुख के साथ पाला बदलते रहे हैं। १९७७ के चुनावों में यहां

विकास, मगर सबका नहीं : अमेठी महल जो राजीव की राजनीति का केंद्र रहा है छाया : मनमोहन शर्मा

के मतदाता जे०पी० की इंदिरा विरोधी लहर में बह गये, तो १९८० में जनता पार्टी विरोधी लहर में बहकर उन्होंने संजय गांधी को विजयी बनाया। १९८४ में सहानुभूति लहर के कारण उन्होंने मेनका गांधी को हराकर राजीव गांधी को रिकार्ड मतों से विजयी बनाया था। अब वी०पी० सिंह की भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राजीव गांधी विरोधी लहर चल पड़ी है। राजनीतिक प्रेक्षक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि संजय सिंह की बगावत और वी०पी० सिंह की लहर—दोनों मिलकर अमेठी के मतदाताओं को राजीव गांधी विरोधी बना देंगे। दिल्ली दरबार भी संजय सिंह को कमजोर नहीं मान रहा। अमेठी में उनके असर को कम करने के लिए दिल्ली दरबार ने व्यापक रणनीति तैयार कर उस पर अमल करना प्रारंभ कर दिया है।

नयी रणनीति : इस रणनीति के तहत कैप्टेन सतीश शर्मा महीने में दस दिन अमेठी संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। स्वयं राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो पिछले करीब ८ महीनों से अमेठी नहीं गये हैं, अब हर तीसरे महीने अमेठी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही राज्यमंत्रिपरिषद के चार सदस्यों प्रमोद तिवारी, पी०के० शर्मा, शिवबालक पासी और श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी पर अमेठी क्षेत्र की सीधी जिम्मेदारी सौंप दी गयी है। वीर बहादुर सिंह हर महीने अमेठी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के सचिव एस०पी० आर्य को भी अमेठी क्षेत्र से संबद्ध कर दिया गया है।

ये सारे कदम अमेठी में संजय सिंह के स्वागत को देखने के बाद उठाये गये। राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद संजय सिंह २३ अगस्त की सुबह अमेठी पहुंचे थे। वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया था। अमेठी राजमहल के प्रांगण में आयोजित एक सभा में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को साहसिक कदम बताते हुए उन्हें बधाई दी।

संजय सिंह की चुनौती : इस्तीफा देनेवाले इन सभी पदाधिकारियों ने अमेठी में संजय सिंह का साथ देने का संकल्प दोहराते हुए राजीव गांधी से तुरंत त्याग-पत्र देने की मांग की। वक्ताओं का कहना था कि अब अमेठी की जनता किसी 'बाहरी व्यक्ति' को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राजीव गांधी को अमेठी की जनता का फिर से जनादेश प्राप्त करना चाहिए। इस सभा को संजय सिंह के पिता तथा अमेठी के भूतपूर्व महाराजा रणंजय सिंह ने भी संबोधित किया। उनका कहना था कि अब राजीव गांधी में अगर जरा भी नैतिकता है, तो वह अमेठी संसदीय क्षेत्र से त्याग-पत्र देकर दुबारा चुनाव लड़ें। उन्होंने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री इस देश का सौदा विदेशियों के हाथ कर रहे हैं, हमारे लिए देश से बढ़कर न कोई नेता है और न कोई पार्टी।"

इसी सभा में संजय सिंह ने कहा, "राजीव गांधी इस देश की अथाह संपत्ति विदेशी बैंकों में

अमेठी में सोनिया कितनी लोकप्रिय

छाया : राजेंद्र कुमार

हरियाणा चुनाव में राजीव परिवार के इटली संबंधों की वजह से भले ही कांग्रेस को नुकसान हुआ हो, मगर अमेठी के लोगों को 'विदेशी बहू' विदेशी नहीं लगती। राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र में जब भी बात चलती है, तो उसमें सबसे पहले जिक्र सोनिया का होता है। खासतौर पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सोनिया से ज्यादा प्रभावित हैं। कारण है, अमेठी में चल रहे विकास कार्य, जिनसे ज्यादा लाभ इन्हीं वर्गों को पहुंच रहा है। सोनिया ने भी अपने को अमेठीमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अमेठी में सोनिया ऐसी लगती ही नहीं कि वह विदेशी हों और भारत के गांवों से अपरिचित हों। बुजुर्गों को सोनिया की पल्लू से सिर ढंकी मुद्रा ज्यादा भाती है। माथे पर बिंदी और पैरों में आलता लगाकर वह किसी भी घर में बेहिचक आती-जाती हैं। और-तो-और लोगों से निकटता बनाने के लिए वह देहाती बोली भी सीख रही हैं।

सोनिया का यह रूप सहज नहीं है और न ही जन्मजात है। उन्हें एक खास योजना के तहत पेश किया गया है। उन्होंने भी इस भूमिका को निभाने के लिए खासा अभ्यास किया है। मेनका का इंदिरा गांधी से संबंध विच्छेद हो जाने के बाद उन्हें मैदान में उतारा गया है। पति के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती गयी। राजीव के चुनाव क्षेत्र में सोनिया ने कई कल्याण कार्यक्रम चला रखे हैं और लोग उनसे काफी प्रभावित भी हैं। ऐसे में यदि किसी दिन सोनिया को चुनाव लड़ाने की मांग उठने लगे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और-तो-और आसपास के चुनाव क्षेत्रों में भी यह प्रतिस्पर्धा पनप सकती है कि वह उनके यहां से चुनाव लड़ें। इसकी वजह भी आसानी से समझी जा सकती है। जाहिर है, सोनिया जहां से चुनाव लड़ेंगी, वह क्षेत्र सभी मंत्रियों और अधिकारियों का लाडला हो जायेगा। इसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है कि खुद अमेठी में सोनिया के समर्थन में नारे लग चुके हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों से सोनिया को खासी लोकप्रियता मिली है। जबकि राजीव गांधी की तेज औद्योगिकीकरण की नीति से काफी लोग नाराज हो गये, क्योंकि इस अभियान में उनकी जमीन अधिगृहीत कर ली गयी।

इलाके के एक सक्रिय कार्यकर्ता राम दुलारे ने कहा, "सोनियाजी ने नेत्रहीनों को आंखें दीं, अपाहिजों की मदद की, अशिक्षितों को शिक्षा दिलवायी और भूखों को खाना खिलवाया। उन्होंने आम आदमी, महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए सब कुछ किया है।" इस लोकप्रियता के चलते सोनिया में राजनीतिक इच्छा जागी है और वह अपनी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहती हैं। मगर, यदि सोनिया ऐसा करेंगी, तो इससे उनकी छवि खराब होगी।

सोनिया अपने पति के अमेठी-दौरों में साथ जाने के अलावा, अकसर अकेले भी जाया करती हैं। सामान्य तौर पर पूर्व रक्षाराज्यमंत्री अरुण सिंह की पत्नी नीना सिंह उनके साथ होती हैं, मगर केवल दुभाषिये की हैसियत से। अब तो सोनिया बिना किसी सहायक के भी चली जाती हैं और भारत के ग्रामीण जीवन को समझने की कोशिश करती हैं। उनकी उपस्थिति राजीव की उपस्थिति ही समझी जाती है।

सोनिया के इस समाज सेवा अभियान में सक्रिय चिकित्सालयों के जरिये लगभग दो लाख रुपए की दवाइयां हर महीने बांटी जाती हैं। आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और स्वरोजगार योजनायें उचित देखभाल के अभाव में ज्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही हैं। मध्यमवर्गीय आदमी उनकी इन चालों को आश्चर्य से देख रहा है। तीन बहुओं की सास रामप्यारी ने कहा, "पति की विनम्रता, शराफत और सभ्यता से सोनिया चुनाव क्षेत्र के लोगों की आंख का तारा बनी हुई हैं।" उसने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, "कुछ शरारती पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव और मेनका के संबंध में दीवारों पर गंदे नारे लिख दिये थे। जब सोनिया ने यह सब देखा, तो बहुत नाराज हुईं और कार्यकर्ताओं से दीवारों को पोतने के लिए कहा। उनका कहना था कि महिलाओं से व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है।" ■

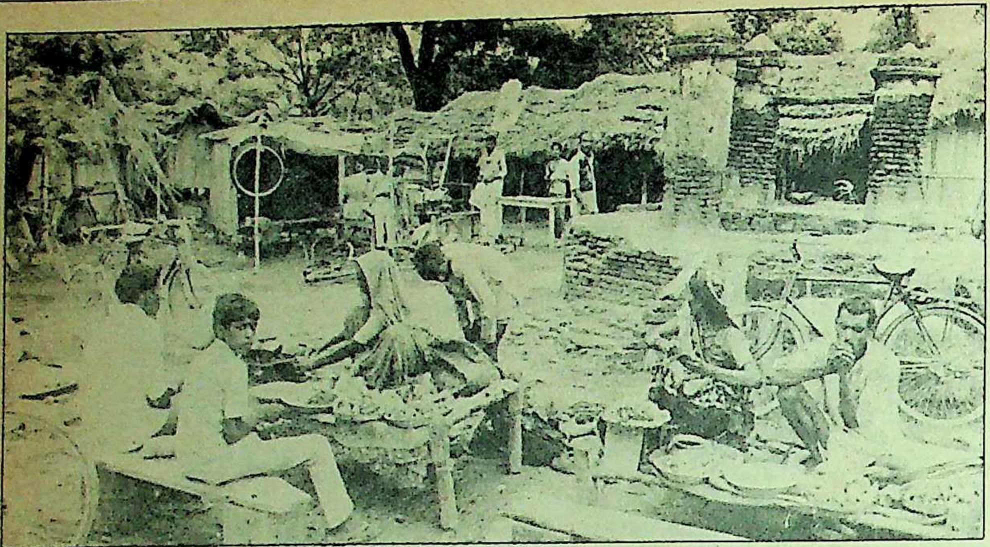

राजीव का आधार

छाया : मनमोहन शर्मा

वीर बहादुर सिंह का कहना था, "संजय सिंह, हरिजन और पिछड़े वर्ग के दुश्मन थे, इसलिए उनके कांग्रेस छोड़ने से अमेठी में इंका के वोट और बढ़ जायेंगे। सही बात तो यह है कि संजय सिंह जहां भ्रष्टतम व्यक्ति हैं, वहीं उनका चरित्र भी ठीक नही है।"

यह सारा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के प्रांगण में लगे एक बड़े तंबू के नीचे हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, हरिजन समाज कल्याण मंत्री स्वरूप कुमारी बक्शी, राज्यमंत्री शिव बालक पासी, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष मोहन सिंह के अलावा अमेठी के अन्य विधायक, कार्यकर्ता व नेता भी उपस्थित थे। ब्लाक प्रमुखों व विधायकों ने संजय सिंह के विरुद्ध जमकर जहर उगला और इंका आलाकमान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।

संजय सिंह की सभा अमेठी राजमहल के

जमाकर देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। उनकी विचारधारा भारतीय न होकर इटली और स्विट्जरलैण्ड से जुड़ी हुई है। राजीव गांधी और उनकी ससुरालवालों ने बोफोर्स तोपों की खरीद तथा अन्य रक्षा सौदों की दलाली में करोड़ों रुपए कमाकर विदेशी बैंकों में जमा किये हैं। घटिया हथियारों के कारण हमारी सेना का मनोबल गिरा है।"

अमेठी की जनता का आह्वान करते हुए संजय सिंह बोले, "अमेठी के लोगों को 'अपनी भूल' सुधारनी होगी। मैं राजीव गांधी को चुनौती देता हूं कि वह अब अमेठी से चुनाव लड़कर देखें। अब देश और प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप का तांडव होगा। देश को बचाने के लिए अमेठी की जनता आगे आये।"

इस सभा में भादर के ब्लाक प्रमुख राम बहादुर सिंह, भेटुआ के ब्लाक प्रमुख रामहर्ष सिंह, संग्रामपुर विकास खण्ड के इंका अध्यक्ष अरुण सिंह, भेटुआ ब्लाक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह, भादर ब्लाक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जगतपाल तिवारी, जिला परिषद सदस्य नंदकुमार सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की।

अमेठी में संजय सिंह की सभा के बाद ही वीर बहादुर सिंह ने भी नये सिरे से मोर्चेबंदी शुरू कर दी। २५ अगस्त को अमेठी संसदीय क्षेत्र में आनेवाले सभी ब्लाक प्रमुखों, जिला परिषद सदस्यों और प्रमुख कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया। इस सभा में अमेठी क्षेत्र के १६ में से १२ ब्लाक प्रमुखों के अलावा सभी प्रमुख कार्यकर्ता और विधायक मौजूद थे। इन सभी ने जहां एक स्वर में राजीव गांधी के प्रति आस्था व्यक्त की वहीं संजय सिंह को जमकर कोसा गया तथा उन पर तीखे आरोप लगाये गये।

एक ब्लाक प्रमुख महेश नारायण सिंह ने कहा कि उनके ब्लाक में, संजय सिंह का न कोई प्रभाव था, न है, न होगा। ब्लाक प्रमुख हाजी सुल्तान का कहना था, "वह आज तक संजय सिंह को नहीं पहचानते।"

साक्षात्कार/सतीश शर्मा

अमेठी का जिम्मा

देशभर की समस्याओं में उलझे प्रधानमंत्री का अपने चुनाव क्षेत्र में न जा पाना, उनकी मजबूरी है। जब कभी वह अमेठी दौरे पर जाते भी हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के कारण उनके और अमेठीवासियों के बीच की दूरी कम नहीं हो पाती। लिहाजा अमेठीवालों ने उन्हें यहां नियमित न आने की छूट दे रखी है। राजीव गांधी की अनुपस्थिति में उनका अपना एक विश्वासपात्र प्रतिनिधि वहां की देख-रेख करता है। प्रतिनिधि नामजद करने की परंपरा संजय गांधी के समय में शुरू हुई थी। तब जे०एन० मिश्रा संजय के सपनों को साकार करने के लिये नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे थे।

राजीव गांधी के पहले 'केयर टेकर' या 'प्रतिनिधि' के रूप में आंध्र प्रदेश के सिद्धार्थ रेड्डी को नियुक्त किया गया था। श्री रेड्डी ने भाषा की दीवार तोड़ने के लिए हिंदी सीखी और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किये लेकिन वह राजनीति के दांव-पेचों से अनभिज्ञ थे। कुछ लोगों को राजीव से उनकी यह निकटता पसंद नहीं आयी। नतीजतन इंका के एक गुट ने साजिश करके उन्हें 'चलता' कर दिया। इसके बाद श्री गांधी ने अपने विश्वासपात्र मित्र अरुण सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी। मगर कुछ ही दिनों बाद अरुण सिंह की 'प्रतिभा' की जरूरत कहीं और महसूस की गयी और वह भी अमेठी को उसके हाल पर छोड़कर चले गये। अरुण सिंह की रवानगी के बाद उनके काम का बड़ा हिस्सा उनके सचिव किशोर को सौंप दिया गया। किशोर आम जनता से आये आदमी थे, लेकिन वह भी वहां अधिक दिन तक नहीं चल सके।

इसके बाद अमेठी में कैप्टन सतीम शर्मा का आगमन हुआ। सतीश शर्मा श्री गांधी के साथ इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। कैप्टन शर्मा जल्दी ही अमेठी के हालात से वाकिफ हो गये। उन्होंने महसूस किया कि अमेठी के लोगों की अंतहीन समस्याएं और उम्मीदें हैं, जिनके पूरा न होने के कारण उनमें निराशा भी है। उन्होंने अमेठी में विकास की गति में तेजी लाने का निश्चय किया, जिससे योजनाओं का लाभ सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंचाया जा सके। वह जानते हैं कि इन्हीं विकास कार्यों के कारण ही लोग राजीव गांधी को चाहते हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार की ढील उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। जाहिर है कुछ लोगों को उनका सख्त रवैया पसंद नहीं आया और उनकी आलोचना होने लगी।

कैप्टेन सतीश शर्मा अपनी कार्यपद्धति के कारण ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पूर्व तक मंत्री रहे जफर अली नकवी का कहना है कि उनके आदेश सामंती दिनों के शाही फरमानों की याद दिलाते हैं। वह ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्रियों को उनकी झाड़ सुननी पड़ी है। उनके लखनऊ दौरे से मंत्रियों में भय की लहर दौड़ जाती है। वह सारे मंत्रिमण्डल को तलब करते हैं और सवालों, आदेशों और डांट-फटकार का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुस्त नौकरशाही को सक्रिय करने के लिए संभवतः इससे अधिक वह कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सतीश शर्मा जल्दी-जल्दी सारे काम होते देखना चाहते हैं और वह किसी भी प्रकार की अक्षमता और प्रमाद को सहन करने की मानसिकता में नहीं हैं और न ही वह प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र की वृहत योजनाओं के संबंध में किसी प्रकार का समझौता करने का इरादा रखते हैं। ■

प्रांगण में और वीरबहादुर सिह की सभा मुख्यमंत्री आवास के प्रांगण में हुई थी। संजय सिह परिवार के सामंती संपर्कों ने वहां यदि भीड़ जुटाई, तो मुख्यमंत्री होने के नाते उनके सामने उनके आवास में जुटे लोग संजय सिह की आलोचना करते रहे, लेकिन अमेठी का आम मतदाता क्या सोचता है? 'माया' ने यह जानने के लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र का व्यापक दौरा किया, तो पाया कि सारे अमेठीवासी यदि संजय सिह को पसंद नहीं करते तो अलग-अलग कारणों से वे राजीव गांधी से भी नाराज हैं।

मतदाता का रुख़ : रायबरेली से अमेठी संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर पहला बड़ा कस्बा पड़ता है—इन्होंना। यहां सड़क के दोनों ओर तथा दुकानों और मकानों पर लगे संजय विचार मंच के हरे-सफेद झंडे अतिथियों का स्वागत करते हैं। मुख्य सड़क के किनारे ही एक ढाबा है। उसके मालिक ठाकुर देव बड़े गर्व से बताते हैं कि राजीव गांधी ने यहां पकौड़ा खाया था और इसके ठीक दस दिन बाद वह देश के प्रधानमंत्री बन गये थे। लेकिन, स्वयं ठाकुर देव के दिन नहीं बदले। आसपास खड़े लोग व्यंग्यपूर्वक कहते हैं, "अपना पकौड़ा रोज खाने के बावजूद दादा तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं—बस टूटी मड़ैया में पड़े हो।"

इन्होंना वास्तव में राजीव गांधी से नाराज है। यहां के लोग अपनी नाराजगी को छुपाते भी नहीं। अनेक बातों से वे असंतुष्ट हैं—यहां मान्यता प्राप्त कोई हाई स्कूल नहीं है। एक जूनियर हाईस्कूल है जो ११० साल पुराना है। कोई अस्पताल नहीं है, कभी-कभार एक सचल चिकित्सालय वाहन यहां पहुंच जाता है। यहां कोई उद्योग नहीं है और रोजगार के अवसर भी नहीं है, लेकिन प्रचार तो बहुत है कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों में करोड़ों रुपए फूंके गये हैं, फिर 'इन्होंना' में ऐसा दयनीय नजारा क्यों है? यहां के निवासी कमर हुसैन और वी०के० जायसवाल का कहना है कि इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसका कारण यही बताया जाता है कि यह क्षेत्र संजय गांधी की विधवा मेनका गांधी का गढ़ रहा है, इस कारण यह उपेक्षित है। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन यह सचाई है कि इन्होंना के विकास पर ध्यान न दिये जाने के कारण ही मुस्लिम-बहुल इस क्षेत्र के लोग राजीव-विरोधी खेमे में चले गये हैं। एक वृद्ध पुरुष का कहना था, "हमारे लिए (राजीव ने) अब तक किया क्या है?" इसी असंतोष की वजह से ही इन लोगों ने संजय सिह का उस समय जोरदार स्वागत किया था, जब वह इस्तीफा देने के बाद लखनऊ से अमेठी जाते हुए इन्होंना से गुजरे थे।

इन्होंना ही नहीं अमेठी के प्रायः सारे मुस्लिम मतदाताओं में गहरा असंतोष है। अयोध्या यहां से काफी करीब है। राम जन्म भूमि—बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण वे कांग्रेस-इ सरकार से खफा हैं। संजय विचार मंच के विधायक अकबर अहमद डंपी का इन पर अच्छा-खासा प्रभाव है। हाल ही में स्थानीय अधिकारियों ने जब डंपी को इन्होंना में गिरफ्तार किया था, तो बताया जाता है कि इसकी खबर सुनते ही मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिह भड़क उठे और डंपी को तत्काल रिहा कर देने के आदेश जारी कर दिये थे। उन्हें भय था कि गिरफ्तारी से डंपी की लोकप्रियता काफी बढ़ जायेगी।

राजीव गांधी के प्रति असंतोष इन्होंना में ही नहीं, बल्कि अमेठी के उन क्षेत्रों में भी देखने को मिला जहां विकास कार्यों की गति बड़ी तेज है। जगदीशपुर के अब्दुल अजीज खान तो दावे से कहते हैं, "यहां के आदमी की तरक्की न हुई है न होगी।" जगदीशपुर का औद्योगिक विकास करने के लिए किसानों की जितनी जमीन सरकार ने अधिग्रहीत की है, उनमें २५ प्रतिशत जमीन अजीज खान और उनके रिश्तदारों की है। अजीज खान को इस बात का गुस्सा है कि इतनी उपजाऊ जमीनों के मुआवजे के रूप में उन्हें सिर्फ १५०० रुपए प्रति बिस्वा (१५१.२५ वर्ग गज) मिला है। उसके हाईस्कूल फेल दो लड़के बेकार हैं। अजीज खान का कहना है, "राजीव और सोनिया गांधी पैसा भी खूब बांटते हैं, लेकिन सारा पैसा बिचौलियों की जेब में चला जा रहा है। नाले बन रहे हैं, ठेकेदारों की खूब आमदनी हुई है, पर हमें क्या लाभ हुआ? हम तो आज भी भूखे-नंगे हैं।" ऐसा ही असंतोष अमेठी संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज, जायस, सलोन, जामों आदि इलाकों में भी देखने को मिला।

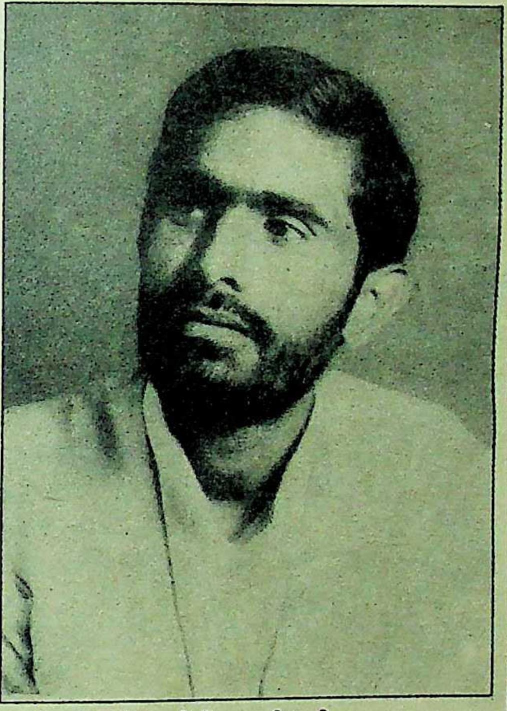
राजीव की जड़ें गहरी हैं : जगदीश पीयूष

असलियत यह है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं भी आसमान छूने लगी हैं। राजीव गांधी हर समय अमेठी में नहीं रह सकते और न ही उनके प्रतिनिधि सतीश शर्मा। और विकास कार्यों को अंजाम देनेवाली सरकारी मशीनरी सिर्फ उन्हीं दिनों सर्वाधिक चुस्त-दुरस्त रहती है, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सतीश शर्मा अमेठी-दौरे पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में अमेठी क्षेत्र के सभी लोगों का संतुष्ट हो जाना संभव नहीं है। उम्मीदों और उनकी पूर्ति के बीच खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अब अमेठीवासी सिर्फ अपनी ही समस्याओं की चर्चा नहीं करते, बल्कि चाय की दुकानों, चौराहों और गांव की चौपालों पर बोफोर्स, फेयरफैक्स और विदेशों में जमा कालेधन पर भी खुलकर बहस होती है। संजय सिह के राजमहल के सामने एकत्र करीब २०० शिक्षित बेरोजगार युवकों में से एक युवक का कहना था, "हम समझते हैं कि विदेशों में जमा सारा काला धन यदि वापस आ जाये, तो हम सब लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती हैं।" राजीव गांधी और वी०पी० सिह का टकराव भी जनचर्चा का विषय बन चुका है।

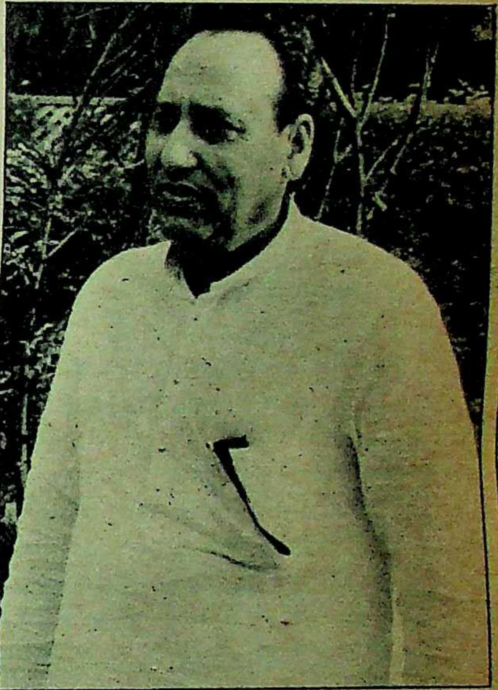
महत्व बढ़ा : के०एन० सिह

भाजपा के जिला सचिव उमाशंकर पाण्डेय का कहना है कि यहां के लोग जागरूक हैं। वे रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं और राष्ट्रीय मामलों पर बहस करते हैं। कांग्रेस-इ से निष्कासित वी० पी० सिह, आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू आदि सब उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, इस कारण यहां के लोग समझ रहे हैं कि ऊपर के स्तर पर कुछ गड़बड़ जरूर है।

यद्यपि राजा विश्वनाथ प्रताप सिह ने राजीव गांधी के खिलाफ जेहाद छेड़ने के बाद अभी तक अमेठी का दौरा नहीं किया है, लेकिन अमेठीवासियों को पता है कि वे देश के अन्य हिस्सों में जनजागरण का कार्य कर रहे हैं। वी०पी० सिह भी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद और बरेली में जनसभाएं की हैं लेकिन अमेठी में वह जन-असंतोष के और गहरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री

के बजाय राजीव गांधी को अपनी आलोचना का निशाना बनाकर संजय सिह राजीव विरोधी जन असंतोष को व्यापक बनाने का ही कार्य कर रहे हैं।

राजीव गांधी की साख : बहरहाल, वी०पी० सिह और संजय सिह के लिए अमेठी से राजीव गांधी को उखाड़ फेंकना सरल नहीं है। अमेठी में जो विकास कार्य हुए हैं और इनका लाभ जिन लोगों तक पहुंचा है वे सब राजीव गांधी के मुरीद बन चुके हैं। गौरीगंज के गंगा प्रसाद गुप्ता का कहना है, "हम उस आदमी के प्रति कृतघ्न और विश्वासघाती कैसे हो सकते हैं, जिसने इस क्षेत्र के लिए इतना कुछ किया है।" एक अन्य कार्यकर्ता का कहना है, "हम राजीव के लिए लड़ने-मरने को तैयार हैं।" और-तो-और स्वयं अमेठी राजघराने के एक ६० वर्षीय माली ने (ठीक उस समय जब महल में संजय सिह की सभा चल रही थी) 'माया' से कहा था, "लागत है राजकुमार पगिलाय गये हैं। बड़े राजा (संजय सिह के पिता) तो सठियाय रहिबै करैं, अब राजकुमारौ पर उनकर असर आइ गवा है। भला राजीव भैया से लड़ाई मोल लइकै, ई कहां जीत पइहैं।"

अमेठी में सोनिया गांधी ही राजीव गांधी की एक बड़ी ताकत बन चुकी हैं। (देखिए बाक्स) दीवारों पर जगह-जगह यह नारा लिखा हुआ दिखाई दे जायेगा—"सोनिया की बात है, सुनहरी शुरुआत है।" इटली की सोनिया गांधी ने बड़े मनोयोग से ठेठ अवधी महिला के तौर-तरीके सीखे लिये हैं और अमेठी की महिलाओं में वह बेहद लोकप्रिय हैं।

सर्वेक्षण : अगर इसी माहौल में चुनाव हो और अमेठी से राजीव के खिलाफ संजय सिह मैदान में उतरें, तो जीत किसकी होगी? यह सवाल अमेठी के करीब दो सौ मतदाताओं से पूछे गये। इनमें व्यापारी, किसान, मजदूर, शिक्षक के अतिरिक्त विपक्ष के लोग भी थे। भाजपा के एक प्रमुख कार्यकर्ता का उत्तर था, "संजय सिह 'न्यूसेंस' हो सकते हैं, लेकिन राजीव के खिलाफ जीत नहीं सकते हैं।"

अमेठी बाजार में कपड़े का व्यवसाय करनेवाले रामसंजीवन का कहना था, "तब राजकुमार सत्ता में थे, सत्ता के बल पर ही अमेठी से सर्वाधिक मतों से जीते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति कतई नहीं रहेगी। राजीवजी के खिलाफ तो दूर, वह अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर लड़ें तो भी जीतना मुश्किल हो जायेगा।"

"आखिर क्यों?" इस सवाल पर उनकी दुकान पर खड़े एक ग्राहक शिवशंकर मिश्र बोले, "जब मंत्री थे तब कितना अकड़कर चलते थे। क्या किया है, उन्होंने अमेठी के लिए? उनकी 'हरकतें' यहां का बच्चा-बच्चा जानता है। यह तो कहिये राजीवजी की वजह से इतने ऊंचे उठ गये थे, अब उन्हीं से दगाबाजी कर दी। इस राजघराने का पुराना इतिहास ही ऐसा रहा है।"

संजय सिंह के जाने से इंका की शक्ति बढ़ेगी : वीर बहादुर सिंह

मुसाफिरखाना के खाद विक्रेता रामेश्वरनाथ कहते हैं, "कहां राजीव भैया और कहां संजय सिह? जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ वह अमेठी की जनता का कैसे होगा? राजमहल में कितनी बार चोरी हुई? किसने लिया वह पैसा? कहां गया वह पैसा, अब जांच हो, तो सब पता चल जायेगा।"

इन दो सौ लोगों में केवल चार व्यक्ति ही ऐसे मिले, जिनका कहना था, "संजय सिह जीत सकते हैं, बशर्ते विश्वनाथ प्रताप सिह अमेठी के पूरे क्षेत्र का चुनाव के दौरान दौरा करें।" लेकिन यह उत्तर देनेवाले लोग न केवल ठाकुर थे, वरन् एक जमाने में ताल्लुकेदार रह चुके हैं। आज भी उनके पास भारी जमीन-जायदाद है। अमेठी क्षेत्र के गैर ठाकुर पूरी तरह राजीव के साथ हैं। हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों का तो बस एक ही उत्तर था, "हम कउनेव राजा-वाजा का नाई जानित। हमरे तो बस सोनिया अउर राजीव हैं।"

मुंशीराम के किसान शिवराम का कहना था, "एक बार इहां के लोग संजय गांधी का हराय के, उकर फल पाय चुका हैं, अब वैसी गलती नहीं करिहैं।"

सुलतानपुर के विधायक देवेंद्र पाण्डेय का कहना था, "संजय सिह के पार्टी से चले जाने के बाद एक बहुत बड़ा पाप कट गया। सही तो यह है कि गंगा नदी में मिलनेवाला एक गंदा नाला पट गया।"

अमेठी संसदीय चुनाव क्षेत्र के शेष चारों विधायक राजीव गांधी के साथ हैं। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिह भी जोड़-तोड़ की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और इस समय उनकी गद्दी सिर्फ उनके इस दावे पर टिकी हुई है कि वह वी०पी० सिह और संजय सिह के असर को बेअसर करने की क्षमता रखते हैं। सुलतानपुर के एक प्रमुख नेता केदारनाथ सिह को फिर से सुलतानपुर में सक्रिय किया जा रहा है। उन्हें संजय सिह के कारण सुलतानपुर की राजनीति से दूर करने के लिए हापुड़ से लोकसभा का टिकट दिया गया था—अब उन पर अमेठी क्षेत्र के ठाकुरों को संजय सिह और वी०पी० सिह के विरुद्ध एकजुट करने का काम सौंपा गया है। वह अपना कार्य असरदार ढंग से कर सकें, इसके लिए उन्हें कांग्रेस-इ का अखिल भारतीय महासचिव बनाकर उनका पार्टी में रुतबा ऊंचा कर दिया गया है।

इन सब कार्यवाहियों पर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमडल से निष्कासित जफर अली नकवी की प्रतिक्रिया थी, "तूफान में मिट्टी का बांध लगा दिया गया है, जिस समय भी बड़ी लहर आयेगी, बहा ले जायेगी।" नकवी की बात में दम नजर आता है; क्योंकि अमेठी के मतदाता राष्ट्रीय लहर से प्रभावित होते हैं। अतः संजय सिह और वी०पी० सिह यदि राजीव गांधी को अमेठी में परास्त करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले पूरे देश में राजीव विरोधी लहर पैदा करनी होगी और जब यह लहर पैदा हो जायेगी तब अमेठी में राजीव गांधी के पराभव को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पायेगी।

ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी इस खतरे को न भांप रहे हों। १०, ११ और १२ अगस्त को उनकी रायबरेली एवं सुल्तानपुर जिलों की यात्रा का मकसद ऊपर से भले सूखे की भयावहता को आंकना रहा हो, लेकिन अंदर से संजय सिह के अलग हटने से अमेठी की जनता पर पड़े विपरीत असर को धोना रहा है। राजीव की इस यात्रा से उनके अंध समर्थकों का जोश बढ़ा है। अमेठी समाचार के संपादक, जिनका ज्यादा समय आजकल संजय सिह के कथित सामंती रवैये को कोसने में जाता, का कहना है, "संजय सिंह को निकाल दिये जाने से राजीव भैया और मजबूत हुए हैं। अब अमेठी के लोग यह नहीं कहेंगे कि आजादी से पहले भी हम राजाओं की धौंस सहते थे और अब भी सहते हैं।" वह संजय सिह की अपनी कोई अहमियत नहीं मानते। वह कहते हैं, "संजय सिह की अपनी कोई चमक नहीं, वह राजीव की रोशनी से चमक रहे थे। अब वह रोशनी छिन गयी।"

लेकिन ऐसा मानना संजय सिह की ताकत को कम आंकना है। इसीलिए राजीव गांधी ने हाल की इस यात्रा में सघन जन संपर्क किया है। गली-गली, कूचों-कूचों में घूमे हैं और विधवाओं के लिए हाथोंहाथ पेंशन की व्यवस्था करवाना और सूखा पीड़ित लोगों को तत्काल राहत मुहैया करवाने जैसे कार्य किये हैं, जिससे जनता पर उनकी यह छाप पड़ सके कि वह अमेठी के दुख-दर्द में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। यद्यपि इस बात का जोरदार खंडन हुआ है कि राजीव गांधी के लिए और कोई चुनाव-क्षेत्र ढूंढ़ा जा रहा है, लेकिन भविष्य में यदि वी०पी० सिह की आंधी ने और जोर पकड़ा, तो खबर सही निकले या खंडन—कुछ कहना मुश्किल है।

—अमेठी से रंजना कक्कड़, आभा डागुर के साथ

करने के
टट दिया
कुरों को
एकजुट
ना कार्य
कांग्रेस-इ
र उनका

के मंत्रि-
की प्रति-
गा दिया
गी, वहा
आता है;
से प्रभा-
ी॰ सिह
करना
विरोधी
हर पैदा
पराभव
पायेगी।

स खतरे
गस्त को
ी यात्रा
हता को
सिंह के
विपरीत
स यात्रा
। अमेठी
आजकल
कोसने
निकाल
हुए हैं।
आजादी
थे और
नी कोई
नय सिंह
रोशनी
गयी।"

ताकत
ांधी ने
या है।
धवाओं
करवाना
मुहैया
ता पर
दुख-दर्द
ात का
के लिए
लेकिन
ने और
—कुछ

के साथ

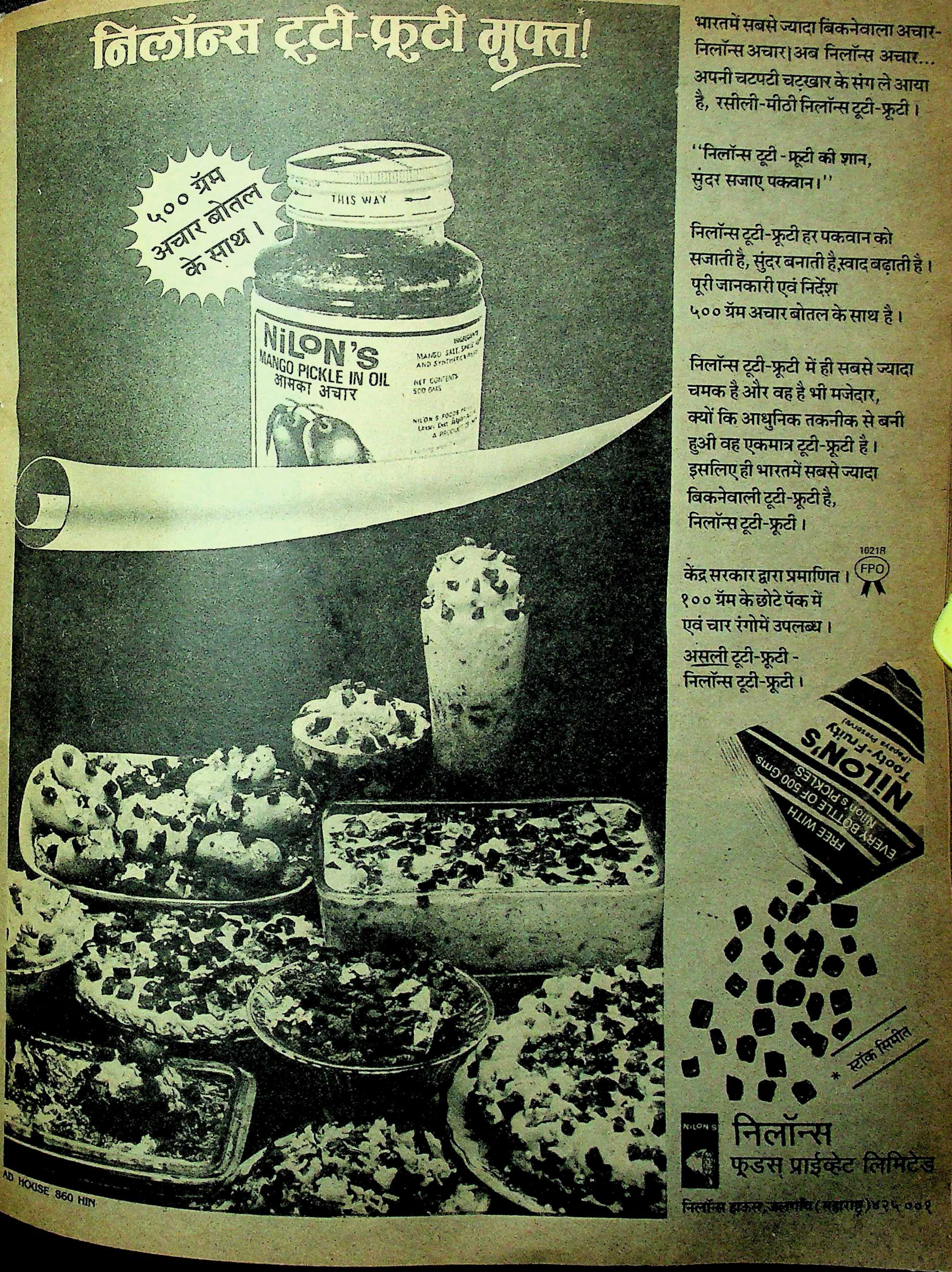
निलॉन्स टूटी-फ्रूटी मुफ्त!*
५०० ग्रॅम अचार बोतल के साथ।
THIS WAY
NiLON's
MANGO PICKLE IN OIL
आमका अचार
NET CONTENTS 500 GMS
NiLON's Tooty-Fruity
FREE WITH EVERY BOTTLE OF 500 Gms. Nilon's PICKLES.
* स्टॉक सिमीत
AD HOUSE 860 HIN

भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाला अचार-निलॉन्स अचार। अब निलॉन्स अचार... अपनी चटपटी चटखार के संग ले आया है, रसीली-मीठी निलॉन्स टूटी-फ्रूटी।

"निलॉन्स टूटी - फ्रूटी की शान,
सुंदर सजाए पकवान।"

निलॉन्स टूटी-फ्रूटी हर पकवान को सजाती है, सुंदर बनाती है,स्वाद बढ़ाती है। पूरी जानकारी एवं निर्देश ५०० ग्रॅम अचार बोतल के साथ है।

निलॉन्स टूटी-फ्रूटी में ही सबसे ज्यादा चमक है और वह है भी मजेदार, क्यों कि आधुनिक तकनीक से बनी हुई वह एकमात्र टूटी-फ्रूटी है। इसलिए ही भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाली टूटी-फ्रूटी है, निलॉन्स टूटी-फ्रूटी।

1021R FPO
केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित। १०० ग्रॅम के छोटे पॅक में एवं चार रंगोमें उपलब्ध।

असली टूटी-फ्रूटी - निलॉन्स टूटी-फ्रूटी।

निलॉन्स
फूडस प्राईव्हेट लिमिटेड
निलॉन्स हाऊस, जलगांव (महाराष्ट्र) ४२५ ००१

विकल्प की तलाश में बदहवास विपक्ष

राजीव गांधी पर गहराते संकट को देख कर विपक्ष बेहद उत्साहित है। लेकिन क्या विपक्ष के पास कांग्रेस-इ का राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प है? विकल्प खड़ा करने के लिए विभिन्न दल जो हाथ-पैर मार रहे हैं, क्या उससे लगता है कि कोई सार्थक और सक्षम विकल्प उभर कर आ सकेगा?

आज विपक्ष की स्थिति उस भूखे वृद्ध के समान है, जिसकी झोली में अखरोट तो आकर गिर रहे हैं, पर उन्हें खा सकने के लिए उसके पास एक अदद सही-सलामत बत्तीसी (दांत) तक नहीं है''—विपक्ष के एक राष्ट्रीय नेता का 'माया' से कहना था। यदि उक्त बुजुर्ग विपक्षी नेता द्वारा पेश किये गये इस सटीक रूपक को आगे बढ़ाया जाये, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले पूरे महीने भर राजधानी में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा की गयी तूफानी कोशिशों व वार्ताओं-बैठकों की मैराथन दौड़ का मकसद आपस में मिलकर कुल बत्तीस अदद दांत इकट्ठे करना था, ताकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति के अखरोट को खाया जा सके। कांग्रेस-इ का विकल्प खड़ा करने की जल्दबाजी में पेश किये गये विभिन्न विपरीत व समानान्तर राजनीतिक फार्मूलों पर कार्यरत विपक्षी नेताओं के मध्य चल रही यह जोड़तोड़ अब एक खोज परिक्रमा बन कर रह गयी है।

कांग्रेस-इ का विकल्प कैसे खड़ा हो? भारतीय राजनीति के इस यक्ष प्रश्न के उत्तर की तलाश का एक चक्र और पूरा हो जाने के बाद उभर कर सामने आयी विपक्षी राजनीति की तस्वीर में, जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं, दलों, असंतुष्ट कांग्रेसियों तथा विश्वनाथ प्रताप सिह के जटिल संबंध और भी ज्यादा पेचीदा होकर सामने उभरे हैं, वहीं एकदम विपरीत और नये राजनीतिक समीकरणों ने जन्म ले लिया है। इसका कारण हैं—पिछले दिनों घटित दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं—प्रथम, जनता पार्टी तथा लोकदल के विलय की कोशिश तथा उसकी असफलता—द्वितीय,

विकल्प : हेगड़े

अकेले : आडवाणी

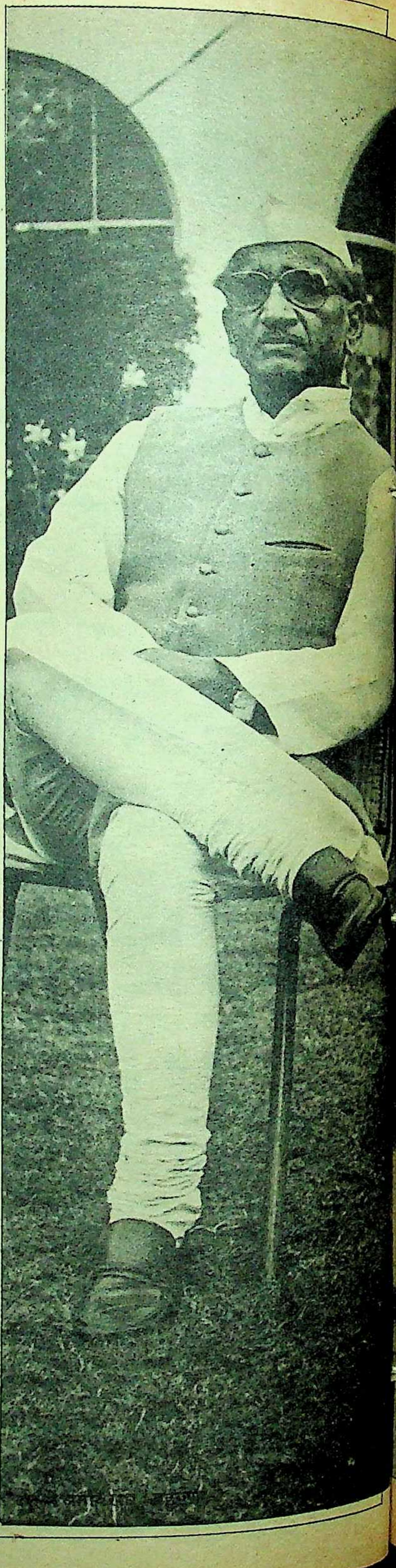

अलग-थलग करने की चा[illegible] [illegible]खर

विश्वनाथ प्रताप सिंह का विपक्षी राजनीति के दक्षिणी ध्रुव (भारतीय जनता पार्टी) से खिसक कर उत्तरी ध्रुव (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के निकट पहुंच जाना। इससे इंका के विकल्प की गुत्थी और उलझ गयी है। अलबत्ता विपक्षी नेताओं के मध्य इस दौरान कई अजीबोगरीब नये रिश्ते उभरकर सामने अवश्य आये हैं।

उत्तर भारत में इंका का विकल्प खड़ा करने की दिशा में पिछले दिनों बहुत तेजी से यह प्रयास किया गया कि किसी तरह जनता पार्टी तथा लोकदल-ब का विलय हो जाये। विपक्षी एकता के नाम पर की गयी इस कोशिश का मकसद था—हिन्दी भाषी क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण दो दलों के विलय से बनी शक्ति को भावी विकल्प की धुरी बनाना। जनता पार्टी में विभिन्न विपक्षी दलों के विलय की पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं। इससे पूर्व संजय विचार मंच, समाजवादी दल व कांग्रेस-स के जनता पार्टी में मिलने की रूपरेखा व शर्तें भी तैयार की गयी थीं। किन्तु इनकी भ्रूण हत्याएं हो गयीं। हरियाणा चुनाव के लगभग एक वर्ष पूर्व जनता पार्टी तथा अविभाजित लोकदल के मध्य भी विलय के प्रयास हुए थे। उस समय इस कार्य में जहां एक तरफ जनता नेता बीजू पटनायक, जार्ज फर्नांडीस व सुरेन्द्र मोहन लगे थे, वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन लोकदल के महासचिव रामविलास पासवान व अजीत सिंह जुटे हुए थे। किंतु तब वह प्रयास अपने शुरुआती दौर में ही दम तोड़ गया। उस समय इस प्रयास में सक्रिय दोनों प्रमुख नेता अब लोक दल-ब के बाहर हो चुके हैं। रामविलास पासवान जनता पार्टी व लोकदल में विलय की असफल कोशिश करते हुए लोकदल से जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं और दूसरे तत्कालीन महासचिव अजीत सिंह अपना अलग लोकदल बनाकर उसके अध्यक्ष हो गये। अजीत सिंह की अब अपने दल व जनता पार्टी के विलय की संभावनाओं पर स्वतंत्र कोशिश जारी है।

एक साथ दो शिकार : हरियाणा चुनाव आते-आते लोकदल-ब व जनता पार्टी के मध्य रिश्ते इस हद तक खराब हो गये थे कि दोनों के विलय की बात सोचना तो अकल्पनीय था ही, बल्कि चुनाव समझौते तक की स्थिति नहीं बन पायी। जनता पार्टी तथा लोकदल (अजीत सिंह) के तीसरे मोर्चे ने देवीलाल का पुरजोर विरोध करते हुए हरियाणा में भारी शिकस्त खायी थी। किंत हरियाणा चुनाव के सिर्फ दो महीने बीतने के बाद ही दोनों दलों के मध्य अचानक तूफानी व नाटकीय ढंग से शुरू हुई विलय वार्ता के एकदम अपने चरम पर पहुंच जाने और फिर चार दिन के अन्दर ही इस पूरी योजना के असफल हो जाने से जहां राजनैतिक समीक्षकों का चौंकना स्वाभाविक था, वहीं इस घटनाक्रम के दौरान उभरे नये समीकरणों को देखना उतना ही दिलचस्प।

जनता पार्टी तथा लोकदल-ब के विलय की इस योजना का शुरुआती खाका हरियाणा चुनाव के बाद से ही धीमे-धीमे बनना शुरू हो गया था। हरियाणा चुनाव में जनता पार्टी के निर्देश के बावजूद जार्ज फर्नांडीस तथा मध्य प्रदेश के युवा नेता रघु ठाकुर के देवीलाल के समर्थन में प्रचार करने के साथ ही जहां एक तरफ दोनों नेताओं की चौ० देवीलाल से घनिष्ठता मजबूत हुई थी, वहीं जनता अध्यक्ष चन्द्रशेखर की इन दोनों से नाराजगी बढ़ गयी थी। हरियाणा चुनाव के बाद लोकदल-ब की अंदरूनी राजनीति में भी उस समय एक नाटकीय परिवर्तन आया, जब चुनाव से पहले तक अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा के निकट रहने वाले चौ० देवीलाल मुख्यमंत्री बनते ही एकदम से बदल गये। बहुगुणा तथा देवीलाल के मध्य कम होती निकटता की गति उस समय और

अधर में : अजीत सिंह

क्रांतिरथी : मुलायम सिंह

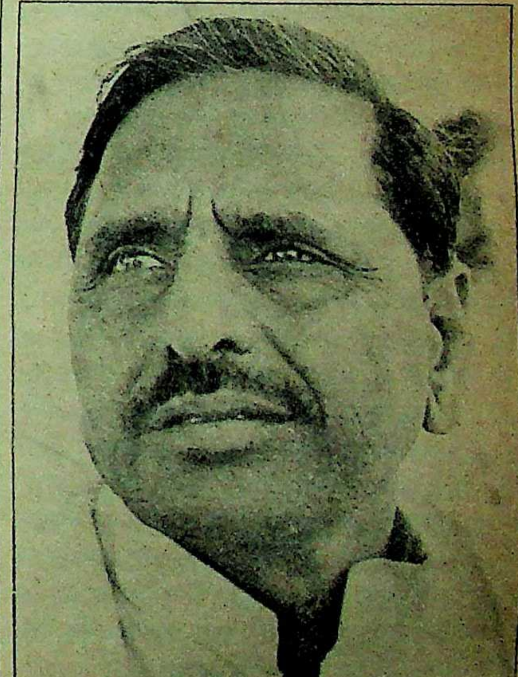

भी तेज हो गयी, जब लोकदल-ब के राष्ट्रीय महासचिव शरद यादव ने सीधे-सीधे देवीलाल के प्रमुख सलाहकार की भूमिका को संभालते हुए बहुगुणा को दरकिनार करने की मुहिम तेज कर दी। चन्द्रशेखर से नाराज जार्ज फर्नांडीस, रघु ठाकुर तथा बहुगुणा से नाराज शरद यादव द्वारा बनाये गये इस विलय-प्रस्ताव की योजना से एक साथ दो शिकार (चन्द्रशेखर तथा बहुगुणा) गिराये जा सकते थे। हरियाणा चुनाव में ऐतिहासिक विजय पाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाले चौधरी देवीलाल को इन तीनों नेताओं द्वारा इस विलय प्रस्ताव के लिए तैयार कर लेने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। इसके दो कारण हैं। पहला, हरियाणा में ऐतिहासिक विजय व राष्ट्रीय सम्मान पाने के बाद से ही यह स्पष्ट होने लगा था कि हरियाणा के इस दुर्जेय चौधरी की महत्वाकांक्षाएं हरियाणा जैसे छोटे से प्रांत में कैद होकर नहीं रह सकतीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कांग्रेस से निष्कासन के तुरंत बाद देवीलाल का उनमें काफी दिलचस्पी दिखाना तथा एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के निर्माण की कोशिश में राजा साहब के साथ उनकी दक्षिण भारत की यात्रा और फिर दोनों का राजस्थान दौरा इसके स्पष्ट संकेत थे। दूसरे देवीलाल हरियाणा चुनाव के दौरान चन्द्रशेखर द्वारा समझौता न किये जाने व अपने जीवन के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण चुनाव में जनता पार्टी द्वारा साथ देना तो दूर उलटे विरोध किये जाने को अभी तक नहीं भूले थे। हरियाणा चुनाव के बाद शायद उन्हें यह भी लगने लगा था कि अब हेमवती नंदन बहुगुणा भी उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रह गये हैं। अत: देवीलाल विलय-वार्ता के हथियार से एक साथ इन दोनों अध्यक्षों को सबक सिखा देने की योजना से तुरंत सहमत हो गये।

एकता प्रयास : दूसरी तरफ जनता पार्टी के द्वारा बहुत पहले ही एकता प्रयासों के लिए गठित की गयी पांच सदस्यीय समिति में ऐसे लोगों की ही बहुतायत थी जो विभिन्न कारणों से या तो चन्द्रशेखर के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं माने जाते या अध्यक्ष-पद के उम्मीदवार हैं। इस समिति के पांच सदस्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री बीजू पटनायक, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीस, इंदु भाई पटेल तथा मधु दंडवते हैं। विलय के पक्षधर नेताओं को यह समझते देर न लगी कि इन पांचों जनता नेताओं की समिति में, एक नेता को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चन्द्रशेखर को संयुक्त दल का अध्यक्ष बनाने का पुरजोर समर्थन करे। देवीलाल द्वारा बीजू पटनायक तथा रामकृष्ण हेगड़े को इस योजना के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। जार्ज पहले से ही इस विलय योजना के निर्माताओं में से एक हैं तथा मधु दंडवते व ईंदुभाई पटेल अपने उदारवादी स्वभाव के कारण इस योजना में कोई बहुत बड़ा अड़ंगा लगायेंगे, इसकी कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं है।

ता युवजन
ATA YUVJ

लोकदल में जाने को आतुर : जार्ज

हरियाणा चुनाव में जनता पार्टी के निर्देश के बावजूद जार्ज फर्नांडीस तथा मध्य प्रदेश के युवा नेता रघु ठाकुर के देवीलाल के समर्थन में प्रचार करने के साथ ही जहां एक तरफ दोनों नेताओं की चौ० देवीलाल से घनिष्ठता मजबूत हुई थी, वहीं जनता अध्यक्ष चंद्रशेखर की इन दोनों से नाराजगी बढ़ गयी थी। हरियाणा चुनाव के बाद लोकदल-ब की अंदरूनी राजनीति में भी उस समय एक नाटकीय परिवर्तन आया, जब चुनाव से पहले तक अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा के निकट रहने वाले चौ० देवीलाल मुख्यमंत्री बनते ही एकदम से बदल गये।

जनता पार्टी की तरफ से वार्ता के लिए पांच सदस्यीय समिति तो बहुत पहले से ही गठित थी, किंतु लोकदल की तरफ से वार्ता में प्रतिनिधित्व कौन करे यह अभी तय होना था। इसके लिए सीधे-सीधे देवीलाल द्वारा जब हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने प्रस्ताव रखा गया, तो सारे राजनीतिक अंकगणित को समझते हुए भी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह बहुगुणा ने इस पूरे कार्य का दारोमदार देवीलाल को ही सौंपते हुए कहा—चौधरी साहब आप खुद ही इस विलय-वार्ता को कर लें तथा जिन लोगों को उचित समझें, उनकी कमेटी बना लें। देवीलाल ने लोकदल की तरफ से चार सदस्यीय समिति गठित कर ली, जिसमें उनके अतिरिक्त कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव तथा शरद यादव थे। समिति में राजस्थान लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा को शामिल नहीं किया गया। जिसका कारण शायद देवीलाल की यह कोशिश थी कि लोकदल की चार सदस्यीय समिति में बहुमत ऐसे लोगों का हो जो चन्द्रशेखर तथा बहुगुणा दोनों को ही हटा कर किसी तीसरे अध्यक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। नाथूराम मिर्धा की बहुगुणा से निकटता सर्वविदित है। देवीलाल को आशा थी कि चार सदस्यीय समिति में उनके तथा शरद यादव के अतिरिक्त शायद मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ रहेंगे। बिहार के एकछत्र लोकदल नेता कर्पूरी ठाकुर को बहुगुणा से निकटता के बावजूद समिति में लेना एक मजबूरी थी, वहां यह मान्यता भी थी कि कर्पूरी ठाकुर चन्द्रशेखर को कतई पसंद नहीं करते।

एक प्रस्ताव : जनता पार्टी तथा लोकदल के इन कुल नौ नेताओं के तैयार हो जाने के बाद इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए देवीलाल द्वारा २२ तथा २३ अगस्त को हरियाणा भवन में विलय-वार्ता की बैठक बुलायी गयी। २२ अगस्त की रात को कोई ठोस बातचीत नहीं हो पायी। उस दिन जार्ज फर्नांडीस भी दिल्ली नहीं पहुंच पाये थे। किंतु २३ अगस्त को इन नौ नेताओं द्वारा दिन भर की गयी लंबी वार्ता के बाद एक आठ सूत्री एकता फार्मूले पर दोनों समितियों की सहमति हुई। इस फार्मूले के प्रमुख सूत्र थे प्रथम—संयुक्त पार्टी का नाम लोकदल रखा जाये, द्वितीय—झंडा लोकदल का हो, पर उस पर चिन्ह जनता पार्टी का हो, चुनाव चिन्ह जनता पार्टी का हो, दल में एक अध्यक्ष तथा एक संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो, अध्यक्ष जनता पार्टी के लोग चुनें, पर ऐसा व्यक्ति जो लोकदल को स्वीकार हो तथा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष लोकदल के व्यक्ति चुनें जो जनता पार्टी को स्वीकृत हो। नीतियां आपस में मिल बैठकर तय कर ली जायें। इस पूरे प्रस्ताव के पीछे यह कोशिश साफ नजर आ रही थी कि लोकदल हेमवती नंदन बहुगुणा को अध्यक्ष पद से हटा दे तथा जनता पार्टी चन्द्रशेखर को। संयुक्त पार्टी का अध्यक्ष बीजू पटनायक या रामकृष्ण हेगड़े को बना दिया जाये तथा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चौधरी देवीलाल को बना दिया जाये। अत्यंत गोपनीय रखे

गये इस समझौता-प्रस्ताव के दोनों दलों में पहुंचते ही होनेवाली प्रतिक्रिया विलय की रूपरेखा बनाने वालों के लिए चौंकाने वाली थी।

किंतु सबसे ज्यादा चौंकानेवाली घटना २८ अगस्त को लखनऊ में हुई। जब सिर्फ ४ दिन पहले हरियाणा भवन में बैठक बुलाकर जनता-लोकदल ब के विलय की सारी रूपरेखा तैयार करने वाले चौ० देवीलाल ने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के मध्य ही लखनऊ के संवाददाता सम्मेलन में इस पूरे 'विलय प्रस्ताव' की खिल्ली उड़ाते हुए घोषणा कर दी कि दोनों दलों के मध्य विलय की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं पर यह आरोप भी मढ़ दिया कि—"अब हर कोई अपने को ही विकल्प मान कर चल रहा है, तो विकल्प कहां से निकलेगा। इसलिए जरूरी है कि संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाये, ताकि विकल्प अपने आप निकले।" इसके लिए उन्होंने एक और राजनीतिक फार्मूला पेश कर दिया कि—"विपक्षी दलों को लोक संघर्ष समितियां बनाकर राजीव सरकार को हटाने के लिए संघर्ष शुरू करना चाहिए।"

जनता-लोकदल विलय द्वारा विकल्प की धुरी तैयार करने के सिर्फ चार दिन पहले तक के अपने फार्मूले से पहले भी चौ० देवीलाल ने एक राष्ट्रीय लोक संघर्ष समिति बनाने का फार्मूला पेश किया था। किंतु तब लोक संघर्ष समिति के इस फार्मूले का संभावित केन्द्र वी०पी० सिंह थे। उस समय उक्त 'फार्मूले' के प्रति आशान्वित देवीलाल ने न केवल अपने मजबूत भाजपाई सूत्रों से बात भी कर ली थी, बल्कि राजमाता सिंधिया तथा कुछ अन्य नेताओं से यह आश्वासन भी प्राप्त कर लिया था कि यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह इस तरह का कोई 'मंच' खड़ा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी शक्ति से भागीदारी करेगी। किंतु इस प्रयोग के बीच में ही अन्यमनस्क वी०पी० सिंह द्वारा अपने भाजपा प्रेम को अधूरा छोड़ वामपंथी दलों की तरफ झुक जाने से लोक संघर्ष समिति की वह योजना कोई शक्ल ले पाने से पहले ही अधर में लटक गयी। वहीं लोक दल-जनता विलय का यह एकदम नायाब फार्मूला अचानक सामने आ गया। २३ अगस्त को हरियाणा भवन में हुई नौ नेताओं की बैठक के बाद अत्यन्त आश्वस्त भाव से निकलते कुछ जनता-लोकदल के नेताओं की बातों से तो यहां तक लगने लगा कि दोनों दलों का विलय तो जैसे होना तय हो चुका है, बस इसकी औपचारिक घोषणा होने में कुछ ही दिनों का समय शेष है।

हरियाणा भवन में हुई उस बैठक से पहले लगभग पिछले १५ दिनों में दोनों पक्षों के कुछ नेताओं द्वारा अलग-अलग एक दर्जन से अधिक गोपनीय बैठकों में तमाम पक्षों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक के ठीक दो दिन पहले रघु ठाकुर ने एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में चन्द्रशेखर को लिखी अपनी चिट्ठी छपवाते हुए यह सार्वजनिक आरोप लगाया कि चन्द्रशेखर किसी भी सूरत में विपक्षी एकता नहीं चाहते हैं। जनता पार्टी अध्यक्ष को यह धमकी भी दी गयी कि वह यदि एकता के मार्ग में आड़े आये, तो उनको दरकिनार कर एकता की जायेगी। किंतु बैठक से पूर्व ही दोनों दलों के अध्यक्षों—हेमवती नंदन बहुगुणा तथा चन्द्रशेखर ने सार्वजनिक घोषणाएं कर दीं कि यदि उनके हटने से विलय संभव होता हो, तो वह तैयार हैं।

देवीलाल को संयुक्त विपक्षी दल के अध्यक्ष के रूप में और ज्यादा ताकतवर चंद्रशेखर उभरते नजर आ रहे थे, जिन्हें अपना राजनीतिक शत्रु मानते हुए सबक सिखाने के लिए उन्होंने यह खाका तैयार किया था। इस बीच चंद्रशेखर तथा हेमवती नंदन बहुगुणा के मध्य और ज्यादा गहरा संवाद स्थापित हो चुका था, क्योंकि दोनों के ही शत्रु समान थे। उधर जनता पार्टी के अंदर की गतिविधियां भी एकता योजना के कर्णधारों के लिए महंगी पड़ रही थीं।

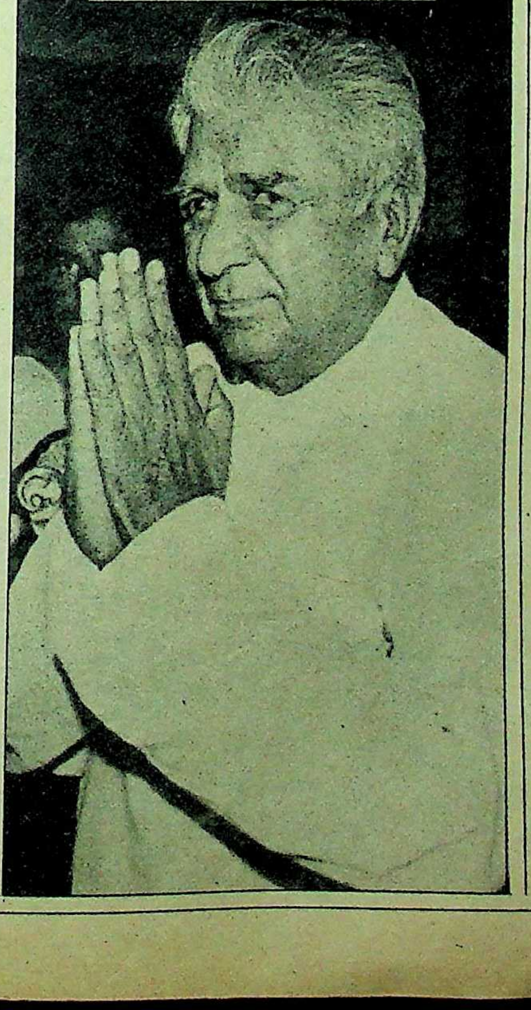

निर्णायक भूमिका : देवीलाल

दिलचस्प घटनाक्रम : चन्द्रशेखर तथा हेमवती नंदन बहुगुणा को विपक्षी एकता का खलनायक घोषित करने के अन्दाज में चलायी गयी मुहिम के बीच में हरियाणा भवन में हुई इन नौ नेताओं की बैठक के बाद घटा राजनीतिक घटनाक्रम और भी दिलचस्प है। बिहार में विरोधीदल के नेता पद से हटाये गये कर्पूरी ठाकुर जो अब तक चन्द्रशेखर विरोधी माने जाते थे, ने बैठक के एक दिन बाद ही २५ अगस्त को जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा चन्द्रशेखर के नजदीकी यशवन्त सिन्हा से हुई अपनी मुलाकात के माध्यम से चन्द्रशेखर तक यह संदेश भेज दिया कि यदि दोनों दलों का विलय हुआ, तो संयुक्त दल का अध्यक्ष चन्द्रशेखर को ही बनाया जाना चाहिए। बुजुर्ग तथा निपुण राजनीतिज्ञ कर्पूरी ठाकुर का यशवन्त सिन्हा से कहना था कि—"यदि संयुक्त दल के अध्यक्ष-पद पर भाई चन्द्रशेखर को नहीं बिठाया गया, तो यह भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पाप होगा।" कर्पूरी ठाकुर लोकदल में हेमवती नंदन बहुगुणा के काफी नजदीक माने जाते हैं। पिछले दिनों बिहार की राजनीति में हुए परिवर्तनों को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर द्वारा यह स्टैण्ड लेना कोई बहुत ज्यादा अप्रत्याशित घटना नहीं थी। यद्यपि यह अलग बात है कि एकता फार्मूले को तैयार करने वालों में यह आशा नहीं थी कि स्थितियां अचानक इतनी तेजी से पलट जायेंगी। चन्द्रशेखर तक यशवन्त सिन्हा के माध्यम से अपना संदेश भेजने से पूर्व कर्पूरी ठाकुर की हेमवती नंदन बहुगुणा से लंबी बातचीत हो चुकी थी। इस वार्तालाप में उत्तर प्रदेश लोकदल के नेता मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव को भी एकता बैठक के बाद बाहर निकलते यह समझते देर नहीं लगी थी कि वह जिस योजना में शरीक होने आये थे, उसका सबसे बड़ा शिकार खुद वही बनेंगे। एक तरफ बहुगुणा तथा दूसरी तरफ चन्द्रशेखर को नाराज करके उत्तर प्रदेश की राजनीति कर पाना मुलायम सिंह के लिए निश्चित रूप से बहुत महंगा पड़ता। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जाट नेता तथा प्रदेश महासचिव राजेन्द्र चौधरी पहले ही मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए सतर्क कर चुके थे कि प्रदेश की राजनीति के इस नाजुक दौर में कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाये, जिससे लोकदल के हितों को चोट पहुंचे। वार्ता समिति में राजस्थान प्रदेश लोकदल के नेता नाथूराम मिर्धा को शामिल न किये जाने से वह पहले से ही इस पूरी योजना व देवीलाल से बेहद नाराज थे। अतः लोकदल में

केवल देवीलाल ही एकमात्र ऐसे अकेले नेता रह गये, जो इस प्रस्ताव के प्रति उत्साहित थे। देवीलाल के एक निकटस्थ सूत्र के अनुसार चौधरी साहब का यह उत्साह भी २६ अगस्त की सुबह उस समय आधा रह गया, जब मुलायम सिंह यादव ने सुबह ही सुबह उनसे जाकर यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि हम लोग चन्द्रशेखर को हटाये जाने की जनता नेताओं की आपसी मुहिम में हिस्सेदारी लेंगे, तो उत्तर प्रदेश में हमारा क्रांतिकारी मोर्चा तो टूटेगा ही, बल्कि मेरे लिए प्रदेश में गंभीर स्थिति पैदा हो जायेगी। उसी सुबह चौधरी देवीलाल तक यह सूचना भी पहुंच चुकी थी कि कर्पूरी ठाकुर चन्द्रशेखर तक अपना यह संदेश भिजवा आये हैं कि वह संयुक्त दल का अध्यक्ष चन्द्रशेखर को ही मानेंगे। उधर नाथूराम मिर्धा के पहले से ही नाराज रहने तथा मुलायम सिंह यादव द्वारा इस समझौते से हाथ खींच लिये जाने के कारण शरद यादव के भी कमजोर पड़ जाने के बाद स्थिति बिलकुल बदल गयी। अब देवीलाल को संयुक्त विपक्षी दल के अध्यक्ष के रूप में और ज्यादा ताकतवर चन्द्रशेखर उभरते नजर आ रहे थे, जिन्हें अपना राजनीतिक शत्रु मानते हुए सबक सिखाने के लिए उन्होंने यह खाका तैयार किया था। इस बीच चन्द्रशेखर तथा हेमवती नंदन बहुगुणा के मध्य और ज्यादा गहरा संवाद स्थापित हो चुका था, क्योंकि दोनों के ही शत्रु समान थे।

उधर जनता पार्टी के अन्दर की गतिविधियां भी एकता योजना के कर्णधारों के लिए महंगी पड़ रही थीं। रामकृष्ण हेगड़े तक कर्नाटक के जनता विधायकों के एक बहुत बड़े वर्ग का नोटिस पहुंच चुका था कि चन्द्रशेखर के बिना किसी भी एकता-प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। जनता पार्टी के कई नेताओं द्वारा इस प्रस्ताव का भी पुरजोर विरोध किया गया कि दल का नाम जनता पार्टी न होकर लोकदल होगा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एफ०एम०लारी, युवा जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीन्द्र भदौरिया सहित तमाम जनता नेताओं का यह मत था कि जनता पार्टी नाम एक क्रांतिकारी जनआंदोलन से निकला है, इसके पीछे जे०पी० आंदोलन का इतिहास छिपा है। इसे मिटाकर एक ऐसा नाम अपना लिया जाये जो किसी एक नेता की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण पैदा हुआ हो, यह स्वीकारना कहां तक उचित है। दूसरी तरफ लोकदल नेताओं को यह भय था कि यदि वह लोकदल नाम छोड़कर जनता पार्टी अपना लेते हैं, तो चौधरी चरण सिंह द्वारा छोड़ी गयी राजनीतिक विरासत लोकदल (अजीत सिंह) के हाथों खिसक जायेगी तथा वह और ज्यादा मजबूत हो जायेगी।

देवीलाल द्वारा उत्तर प्रदेश दौरे पर आने के दौरान उ०प्र० लोकदल नेताओं द्वारा उन्हें यह स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया कि यदि दोनों दलों के अध्यक्षों को हटाकर संयुक्त दल का अध्यक्ष जनता पार्टी के बीजू पटनायक या हेगड़े को बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में इससे कोई लाभ मिलना तो दूर, दल को नुकसान ही होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि नाराज चन्द्रशेखर समर्थकों ने उनसे दामन छोड़ लोकदल अजीत सिंह को साथ ले लिया, तो स्थिति और भी विकट हो जायेगी। देवीलाल निश्चय ही यह नहीं चाहते थे कि संयुक्त दल के अध्यक्ष चन्द्रशेखर हों। इससे ज्यादा तो उन्हें लोकदल-ब के मौजूदा अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ रहने में ज्यादा स्वतंत्रता नजर आ रही थी। टूटते हुए इन समीकरणों को देखने के बाद एकता-वार्ता के चार दिन बाद बिना समय गंवाये लखनऊ के संवाददाता सम्मेलन में देवीलाल ने खिल्ली उडाते हुए आगे के रास्ते बंद कर दिये।

किंतु इस पूरे घटनाक्रम का शायद सर्वाधिक रोचक पहलू अभी सामने आना बाकी है। हर स्थिति का लाभ उठा लेने की राजनीति में प्रवीण चन्द्रशेखर ने २ सितंबर को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहकर कि एकता प्रस्ताव अभी समिति ने दल को सौंपा है तथा इस पर दल के संविधान के अनुसार विचार होगा—इस योजना को एक नया मोड़ और दे दिया है। देवीलाल द्वारा लखनऊ में अपने ही एकता प्रस्ताव की खिल्ली उड़ा कर खत्म कर देने के बाद चन्द्रशेखर द्वारा इसे जीवित रखने की रणनीति के बाद एक बार फिर पूरी राजनीति पलट गयी है। क्या चन्द्रशेखर तथा बहुगुणा दोनों मिलकर अपने विरुद्ध तैयार की गयी इस योजना को अपने ही पक्ष में पलट पाने में सफल होंगे या यह दम तोड़ता एकता-प्रयास विपक्षी नेताओं में कटुता फैलाकर समाप्त हो जायेगा। इसका उत्तर अभी दे पाना कठिन है।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

—पुनीत टंडन

चुनौतियां : कर्पूरी ठाकुर

> **देवीलाल निश्चय ही यह नहीं चाहते थे कि संयुक्त दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर हों। इससे ज्यादा तो उन्हें लोकदल-ब के मौजूदा अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ रहने में ज्यादा स्वतंत्रता नजर आ रही थी।**

रेशमि बालोंका जूँ, लिख और खुशकी से रक्षण किजिए।
अल्कोहोल रहित आयुर्वेदिक तेलयुक्त सुजानिल्स
लाइसिल
सुवासित जूं नाशक
LiCEL
LiCEL
सुजानिल
केमो इंडस्ट्रिज
६९ वानवडी, कोंढ़वा रोड,
पुणे ४११ ०४०
EXPRESSO/87/HIND

BD 525/HIN

सैज़ारी

पॉलिएस्टर वूल, वर्स्टेड और पॉलिएस्टर ब्लेंडेड सूटिंग्स

बॉम्बे डाइंग
स्थापना १८७९

BD 525/HIN

ठाकुर बनाम ब्राह्मण:
ामत राजाओं की या राजीव की ?

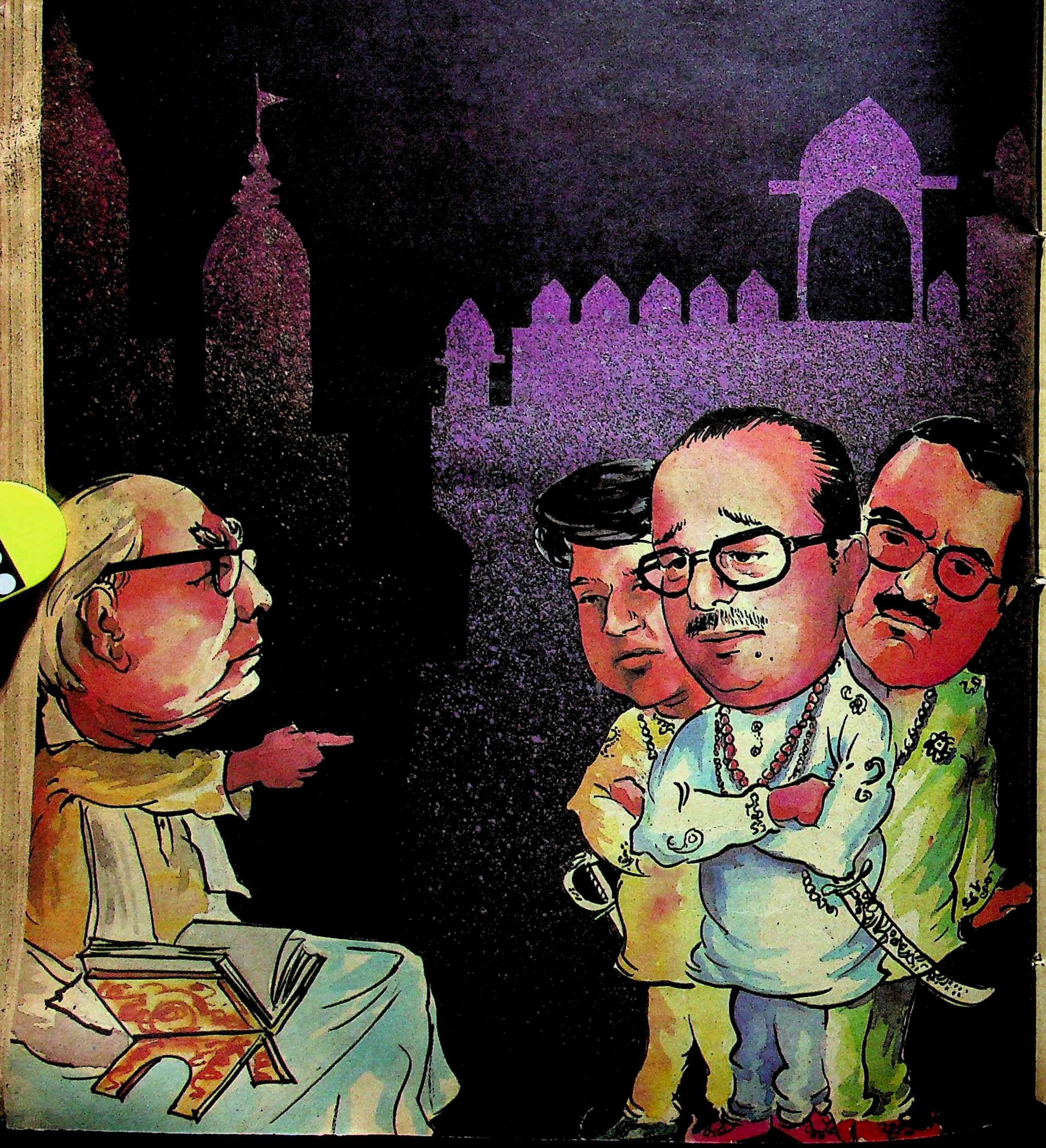

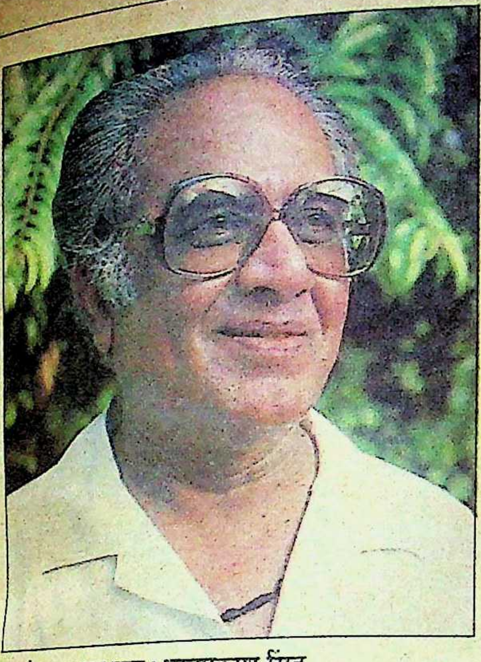

सामंतवाद मर गया : भानुप्रकाश सिंह

सामंत नहीं, जनसेवक : कर्ण सिंह

छाया : सुनील सक्सेना

विवाद निराधार है : पी०एन० सुकुल

जब मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष और एस० निर्जलिंगप्पा जैसे असंतुष्टों ने श्रीमती गांधी के सामने मुसीबत खड़ी की थी, तो पार्टी के बड़े विभाजन से उत्पन्न संकट से उबरने के लिए उन्होंने नारा दिया था—'गरीबी हटाओ'। अब जब राजीव गांधी वैसी ही आफत में फंसे हैं, तो उन्होंने कमलापति त्रिपाठी व कल्पनाथ राय जैसों को छूट दी है कि वे नारा लगायें—'राजा-महाराजा हटाओ'। साथ ही उन्होंने वी०एन० गाडगिल, के०एन० सिंह और के०आर० गणेश को उस 'सोशलिस्ट फोरम' को पुनर्जीवित करने के लिए आशीर्वाद भी दिया है, जिसे श्रीमती गांधी ने मरने दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संकट में बुरी तरह ग्रस्त राजीव को बचाने का पराक्रम इन्हीं नेताओं में है। लेकिन विडंबना यह है कि इनके सामंतवाद-विरोध और समाजवाद की गुहार ने राजीव गांधी की पिछले तीन साल की आर्थिक तथा अन्य नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर राजीव गांधी की छवि यह बन रही है कि वह अपने पूर्व वित्तमंत्री के 'आर्थिक-पापों' के या तो असहाय तमाशबीन थे या फिर उनमें सक्रिय भागीदार। क्या 'त्रिपाठी और गाडगिल ऐंड कंपनी' इसलिए दुधारी तलवार भांजने में लगे हैं, ताकि उनको दुबारा सत्ता में पांव टिकाने की जगह मिल जाये—चाहे राजीव का कुछ भी बने? ताज्जुब तो यह है कि जब 'राजा-महाराजा हटाओ अभियान' के कारण ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच 'युद्ध' तेज होता जा रहा है, तो राजीव गांधी मौन क्यों हैं? क्या उनकी इस बात में मौन सहमति है कि भूतपूर्व राजा-महाराजाओं का पार्टी में होना ही रोग की जड़ है? या राजीव गांधी इस समय इतने भ्रांत हैं कि उनको यही नहीं पता चल रहा कि वह क्या करें और क्या नहीं?

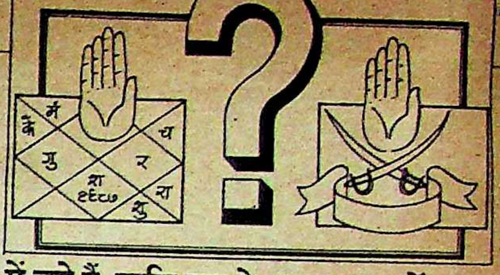

बोफोर्स की तोपों से विपक्ष राजीव-सरकार पर कहर बरसा ही रहा है, अब टोपीधारी कांग्रेसियों ने भी इन तोपों की ओट में अपने मोर्चे मजबूत करने शुरू कर दिये हैं। इन कांग्रेसियों को राजीव ने अप्रत्याशित विजय के मद और भारत को २१वीं सदी में ले जाने की धुन में न केवल दूध की मक्खी की तरह सत्ता से निकाल फेंका था, बल्कि पार्टी की स्वर्णजयंती के अवसर पर सरेआम उनको एक प्रकार से दलाल संस्कृति के ध्वंसावशेष की संज्ञा भी दी थी। मौके की घात में बैठे इन सभी नेताओं को अब अफवाहों से घिरे राजीव से अपमान और उपेक्षा का बदला लेने का सुनहरा अवसर मिल गया है। मजे की बात यह है कि यह कार्य वह पार्टी को सशक्त बनाने और उसे जनता के करीब ले जाने के नाम पर सिद्धांतों का वास्ता देकर कर रहे हैं—जबकि इन सिद्धांतों पर वे स्वयं कभी अडिग नहीं रहे।

दरअसल, १९७१ में उठाये गये 'गरीबी हटाओ' के नारे की अभूतपूर्व सफलता के पश्चात पंडित कमलापति त्रिपाठी ने हाल में पार्टी से निकले विश्वनाथ प्रताप सिंह और संजय सिंह पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए 'राजा हटाओ' का जो नारा उछाला है, उससे पूरी पार्टी में उथल-पुथल मच गयी है। इससे एक ओर भूतपूर्व राजघरानों से संबद्ध लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गयी है, तो दूसरी ओर जातिवाद के तहत ब्राह्मणों-ठाकुरों में ठन गयी है। इस पर तुर्रा यह कि 'कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम' की स्थापना हो गयी है, जिसके माध्यम से कुछ लोगों ने सामंतवाद के खिलाफ झंडा खड़ा करके अपने को गरीबों का एक मात्र हमदर्द और वामपंथी नीतियों का कट्टर पक्षधर उद्घोषित किया है।

इस सबसे एक ही बात जाहिर होती है कि

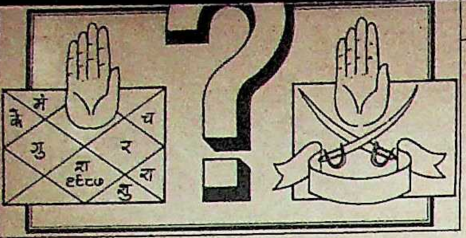

शिवेंद्र बहादुर सिंह

खैरागढ़ के भूतपूर्व शासक और वर्तमान सांसद शिवेंद्र बहादुर सिंह राजीव गांधी के दून-सखा हैं। उन्होंने 'माया' को बताया, "हमने अपने लोगों और देश की सेवा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। हाल में खड़ी हुई विरोधियों की फौज में ऐसे कितने लोग हैं, जिन्होंने एक परिवार से तीन लोगों—स्वयं, पिता एवं माता को पार्टी और सरकार की सेवा में अर्पित किया हो? वे कितना 'कर' देते हैं और उनका १९४७ में कितना 'बैंक-बैलेंस' था और अब कितना है?"

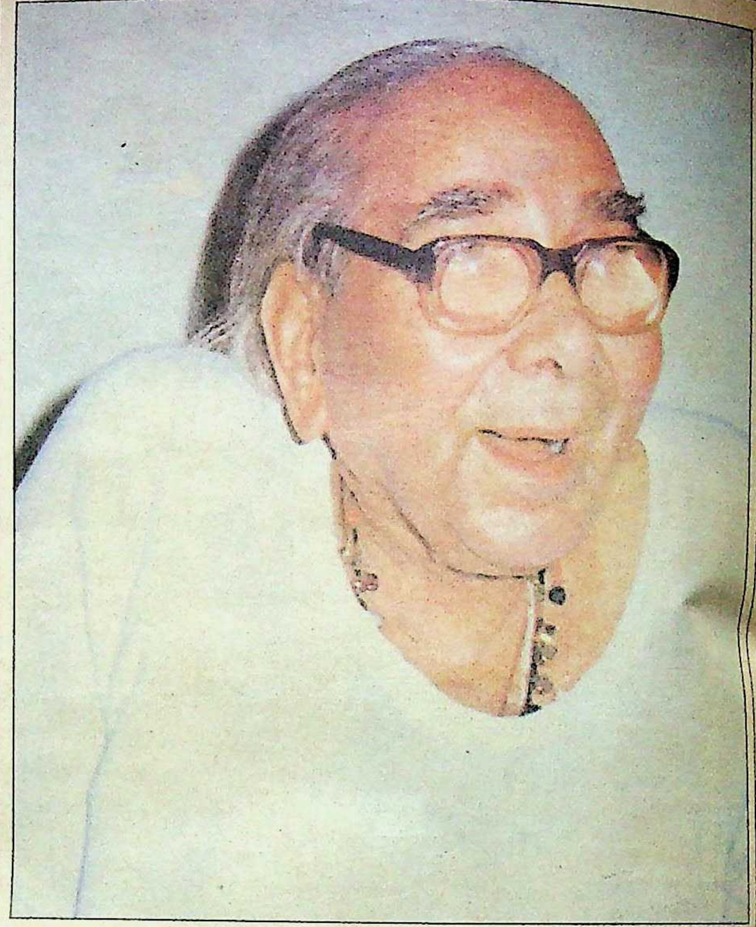
जातिवाद-विवाद के जनक : कमलापति त्रिपाठी

छाया : विजय सिंह

पुराने घोड़ों ने पुराना राग हिनहिनाना शुरू कर दिया है। इस सबका कारण है राजीव गांधी की संकटपूर्ण स्थिति। इस स्थिति का लाभ उठाकर पुराने लोग उनका कवच बनने का दिखावा कर रहे हैं और उनको बाध्य कर रहे हैं कि वह इन लोगों को अपनी बैसाखी समझें, चाहे इनकी बातें कितनी ही परस्पर विरोधी क्यों न हों।

विज्ञान भवन में 'कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम' के समापन सत्र में पार्टी के पुराने सिपहसालारों के बीच हुए वाग्युद्ध का दृश्य दर्शनीय था। यद्यपि वहां स्वयं राजीव गांधी मौजूद थे और उनके राजनीतिक कान-आंख माखनलाल फोतेदार भी वहीं थे, लेकिन इन युयुत्सु सिपहसालारों को इसकी कोई चिंता नहीं थी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र उस समय आग बबूला हो उठे, जब उन्होंने एक के बाद-एक लंबे भाषण सुने, जिनमें इस बात की आलोचना कूट-कूटकर भरी थी कि पिछले कुछ सालों से सरकार समाजवाद-विरोधी नीतियों पर चल रही है। यहां तक की स्वभाव से संयमी आर०जी० रंगा और गंभीर माने जाने वाले पी० एन० सुकुल को भी इस आलोचना के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी। बाध्य होकर पी० शिवशंकर को मंच से नीचे उतरना पडा और उन्होंने जैसे-तैसे श्रीपति मिश्र को ठंडा किया।

मतभेद प्रखर : इस बैठक का ऊपरी उद्देश्य तो यह था कि राजीव गांधी जिस आपदा के पाश में हैं, उसको काटने में वह सक्षम हो सकें, लेकिन इसका कुपरिणाम यह हुआ है कि जो लोग तहेदिल से राजीव गांधी का समर्थन कर रहे थे, उनके बीच मतभेद और शाणित हो गये हैं। इस संदर्भ में एक मंत्री ने 'माया' को बताया, "राजीव गांधी ने इस फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए इस उम्मीद के साथ सहमति दी थी कि इससे पार्टी की एकता मजबूत होगी, लेकिन अब लगता है वह इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं।" श्रीमती गांधी चतुर थीं, इसलिए उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि जो लोग इस फोरम में सक्रिय हैं, वे लोग मंत्री-पद व अन्य लाभ पाने के लिए एक दबाव-गुट बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस फोरम को ध्वस्त कर दिया था। एक प्रमुख मंत्री ने अपनी नाराजी व्यक्त करते हुए 'माया' से कहा, "के०आर० गणेश और के०एन० सिंह किस मुंह से वफादारी के प्रमाण बांट रहे हैं, क्या लोग नहीं जानते कि उन्होंने श्रीमती गांधी के साथ क्या सलूक किया था?" यह कैसे हो सकता है कि के०एन सिंह ऐसे आरोप बर्दाश्त कर लें। नतीजतन राजीव-भक्तों के बीच खुला संग्राम छिड़ गया है।

इधर पंडित कमलापति त्रिपाठी के मन में भी राजीव के प्रति सहानुभूति का पुनरोदय हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजा-महाराजा सत्ता पर हावी होने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंडितजी की इस पुनर्अंकुरित सहानुभूति को राजीव गांधी अमिलावटी मान रहे हैं। क्योंकि पंडितजी के उपदेश पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। नरसिंहगढ़ के भूतपूर्व महाराजा और श्रीमती गांधी के काबीना में राज्यमंत्री रहे भानुप्रकाश सिंह ने पंडितजी के खिलाफ मोरचा बांधते हुए कहा है, "सामंतवाद तो मर गया, अब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद।" भानुप्रकाश सिंह के विचार में राजीव गांधी को अस्थिर करने की साजिश ब्राह्मण रच रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि ४० साल पहले सारी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो चुका है, ३५ वर्ष पहले १९५२ में जमींदारी की समाप्ति हो चुकी है, १८ साल पहले १९६९ में श्रीमती गांधी द्वारा राजाओं का प्रीवी-पर्स खतम हो चुका है—ऐसी स्थिति में अब सामंती तत्वों के सफाये की गुहार लगाने की तुक क्या है? इसका मतलब है कि नेहरू और श्रीमती गांधी ने जो कुछ किया, वह सब बेमतलब था? इससे राजीव गांधी सीधे-सीधे लांछित होते हैं, क्योंकि अपने नाना और मां की तरह उन्होंने भी भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को अपनी सरकार और पार्टी से जोड़ रखा है। (देखिए बाक्स)। भानु प्रकाश सिंह का मानना है कि वास्तव में यह राजनीतिक समझदारी है कि राजा-महाराजाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए उनको कांग्रेस से जोड़ा गया।

उल्लेखनीय है कि १९४८ में सरदार पटेल के प्रयत्नों से सभी रियासतों के विलय के बाद, प्रमुख रियासतों के स्वामियों को राज्यपाल और

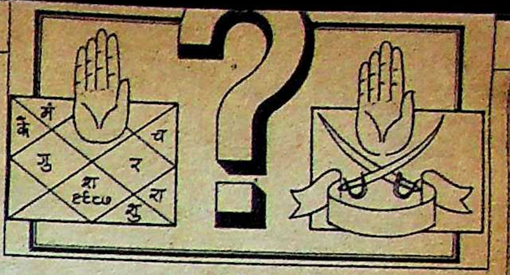

राजप्रमुख जैसे पद दिये गये थे। इनमें से ज्यादातर वे राजा-महाराजा थे, जिन्होंने विलय को स्वेच्छा से स्वीकार किया था और जो कांग्रेसी नेताओं के करीब थे। इसका सीधा-सा कारण था इन लोगों का अपने क्षेत्रों में बेइंतहा असर और प्रशासन का अनुभव। इनमें ज्यादातर लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते थे। इससे विलय भी सहज स्वीकृत हुआ और कांग्रेसी सरकारों को जमने में भी सुविधा हुई। डा० कर्ण सिंह गर्व के साथ कहते हैं, "सामंतवाद से लोकतंत्र की यात्रा की मैंने अगुवाई की थी।" डा० कर्ण सिंह श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में तरुणतम मंत्रियों में से थे। अब यदि उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जनता-काल में श्रीमती गांधी को छोड़ने का पाप किया था, तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रीमती गांधी को छोड़ने वाले लोगों में 'सर्वहारा' लोगों की संख्या तो और भी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, वीरेंद्र पाटिल तो न केवल श्रीमती गांधी से अलग हुए थे, बल्कि उन्होंने तो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। लेकिन आज वही वीरेंद्र पाटिल राजीव गांधी की पार्टी के सम्माननीय सदस्य हैं। डा० कर्ण सिंह इस बात को बेजा मानते हैं कि किसी की इसलिए भर्त्सना की जाये कि वह हरिजन के घर में पैदा हुआ है या किसी राजघराने में। जन्म पर किसी का बस नहीं है। किसी व्यक्ति को आंकने का पैमाना उस व्यक्ति की कार्यकुशलता और उसका पिछला कार्य होना चाहिए।"

इतिहास : यदि आजादी के बाद कांग्रेस और देश के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कि राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में खासकर तथाकथित सामंती तत्व बाधक सिद्ध हुए हों। उदाहरण के लिए कश्मीर में डा० कर्ण सिंह के बजाय शेख परिवार ज्यादा सामंती सिद्ध हुआ है। डा० कर्ण सिंह तो राज्य को छोड़कर श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में आ गये थे। उन्होंने एक कुशल मंत्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। इधर माधव राव सिंधिया भी एक सक्षम मंत्री सिद्ध हुए हैं—यह बात अलग है कि विरासत को लेकर उन पर संगीन आरोप लगाये जा रहे हैं। भूतपूर्व रजवाड़ों के कुछ वंशजों ने आम आदमी के लिए काफी काम भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए अर्जुन सिंह बल देकर कहते हैं, "कांग्रेस के हर कार्यक्रम को, चाहे वह भूमिहीन मजदूरों से संबंधित रहा हो या हरिजनों से संबंधित या फिर समाज के कमजोर वर्ग के मुतल्लिक —मैंने निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया है। मैं इस बात को पसंद करूंगा कि मेरे बारे में जो विचार बनाया जाये, उसका आधार मेरा वह योगदान होना चाहिए जो मैंने पार्टी के कार्यक्रमों को लागू करने में दिया है—चाहे वह काम कितना ही थोड़ा रहा हो।"

उनके कार्यकाल में जिन भूमिहीन मजदूरों ने सरकारी या निजी भूमि पर अपने मकान बना लिये थे, उन सबको उन्होंने निःशुल्क पट्टे दिये।

श्रीमती गांधी के तरुणतम मंत्री : कर्ण सिंह

छाया : सुनील सक्सेना

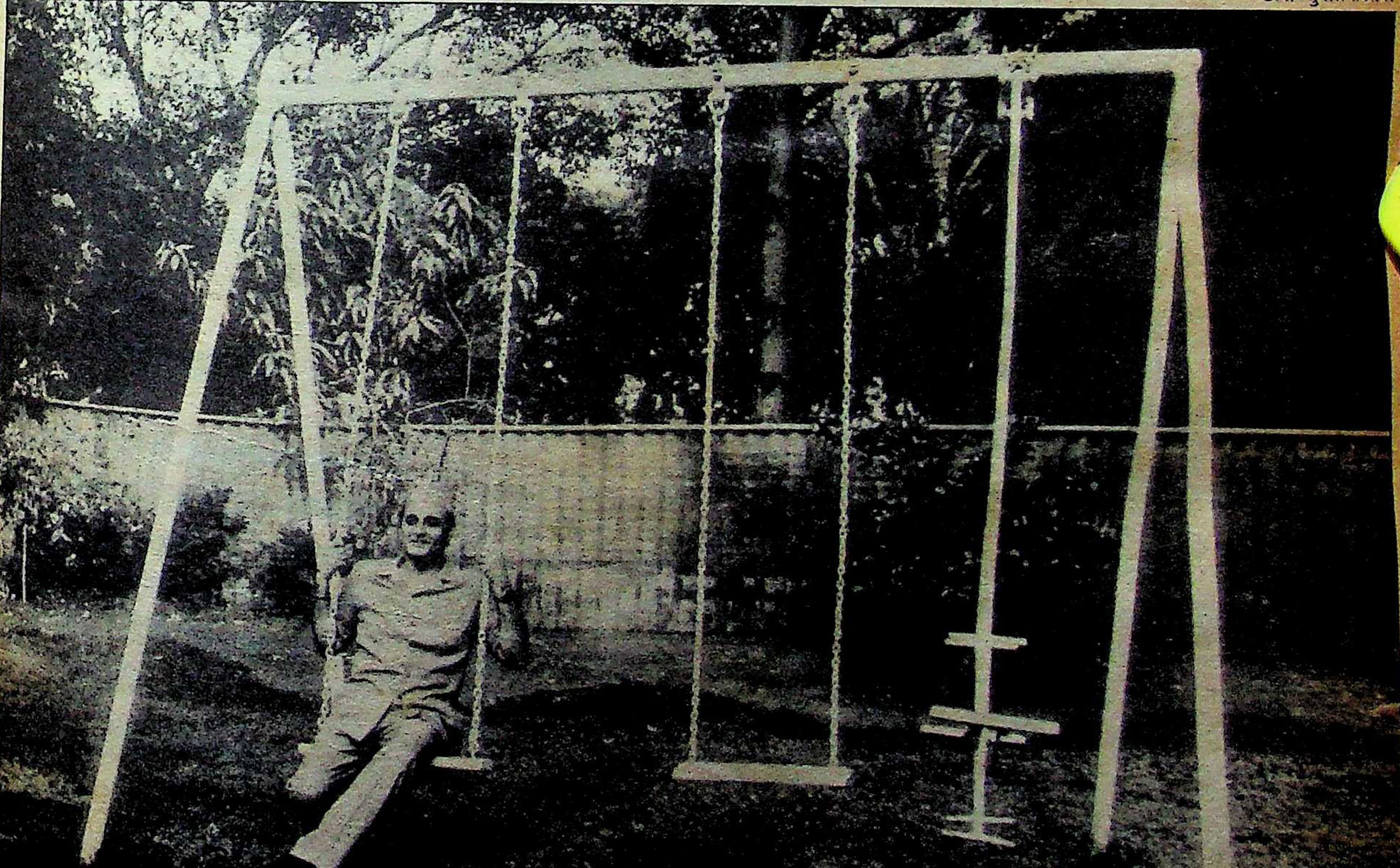

छाया : सुनील सक्सेना

"मुट्ठी भर सामंत वी०पी० सिंह के पीछे एकत्र दिखायी दे रहे हैं, किंतु पार्टी में सत्ता-संघर्ष नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि हरेक ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य को यह पूर्ण विश्वास है कि राजीव गांधी के अलावा दूसरा कोई पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता। पूरा विवाद व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण आरंभ हुआ है। किंतु जो लोग सामंतवाद के विरुद्ध आज हौआ खड़ा कर रहे हैं—मसलन कमलापति—वे पार्टी में लंबे समय से हैं। वे उस पूरे समय खामोश क्यों थे?" सोशलिस्ट फोरम के गठन की क्या तुक है, जबकि पार्टी स्वयं समाजवाद-समर्थक है? क्या इसका मतलब है कि जो इसके सदस्य हैं, वही समाजवादी हैं? इससे आंतरिक विभाजन की संभावना है।"

—पी०एन० सुकुल

यह कार्य १९८१ में हुआ और उसके बाद भोपाल में झुग्गी झोंपड़ियों में रहनेवालों को बिजली मुहैया की गयी। अर्जुन सिंह जानते हैं कि आक्रमण के मुख्य निशाना वही हैं, इसलिए वह ज्यादा तिक्तता के साथ सामंतवाद के आरोप का खण्डन करते हैं, "मां-बाप का चुनाव मैंने नहीं किया। शायद दूसरों में ऐसा करने की प्रतिभा हो।" वह कहते हैं, "मैं १९६० में कांग्रेस में शामिल हुआ था। अब २७ साल हो चुके हैं। मैं चुनौती देता हूं कि कोई एक भी घटना बता दे, जिससे मेरी निष्ठा पर उंगली उठायी जा सके।" सामंती पृष्ठभूमि के अधिकांश लोग ऐसी ही चुनौती दे रहे हैं, हालांकि कुछ यह चुनौती विनम्रता से दे रहे हैं, तो कुछ क्षोभ और क्रोध के साथ।

ब्राह्मणवाद के पुरोधा : कमलापति त्रिपाठी

असली इरादा : भूतपूर्व राजाओं की यह सर्व-सम्मत राय है कि पार्टी के कुछ स्वार्थी और तिकड़मी तत्व राजीव गांधी से अधिकतम फायदा उठाने के लिए भूतपूर्व राजा-महाराजाओं और राजीव गांधी के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और संजय सिंह राजीव गांधी को छोड़ गये हैं, लेकिन इसके कारण त्रिपाठी और राय को कोई हक नहीं मिल जाता कि वे सभी पूर्व राजा-महाराजाओं पर कीचड़ उछालें। क्योंकि ऐसे आरोपों से ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच घृणित जातिवाद को बल मिलता है, जिसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

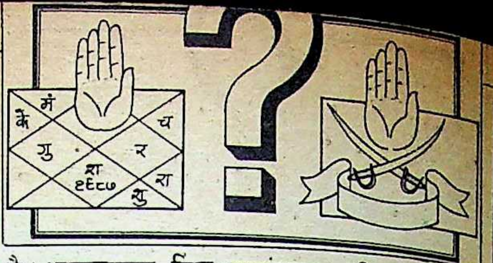

इसी विवाद का दुष्परिणाम है कि इन दोनों जातियों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि राजीव गांधी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको सत्ताच्युत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भानुप्रकाश सिंह सामंतवाद की प्रवृत्ति को जन्मजात नहीं मानते। वह कहते हैं, "सामंतवाद एक प्रकार की मानसिकता है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सत्ता से पैदा होती है।" वह कहते हैं, "क्योंकि सामंतवाद के उन्मूलन के बाद अब जन्मजात सामंतों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अब हम नवसामंतों द्वारा शासित हैं जो जन्मजात सामंतों से भी बदतर हैं।" यह बात सही भी है। यह सभी जानते हैं कि

उमाशंकर दीक्षित

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

कमलापति त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित व द्वारिका प्रसाद मिश्र की चालाक तिकड़ी राजीव गांधी को अपने कब्जे में लेने के लिए एकजुट हो गयी है।

जगजीवन राम को यह बात पसंद थी कि लोग उनके चरण छुएं, इसी तरह गोविंद बल्लभ पंत भी इस बात को पसंद करते थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी को चरण छुआना कितना प्रिय है, यह सभी जानते हैं। दूसरी ओर लोकतांत्रिक जवाहरलाल नेहरू को इस बात से नफरत थी। दरअसल पूर्व राजा यह महसूस करते हैं कि इन सारे आरोपों का असली मकसद ब्राह्मणों का एकाधिपत्य स्थापित करना है और राजीव गांधी से सत्ता हथियाना है।

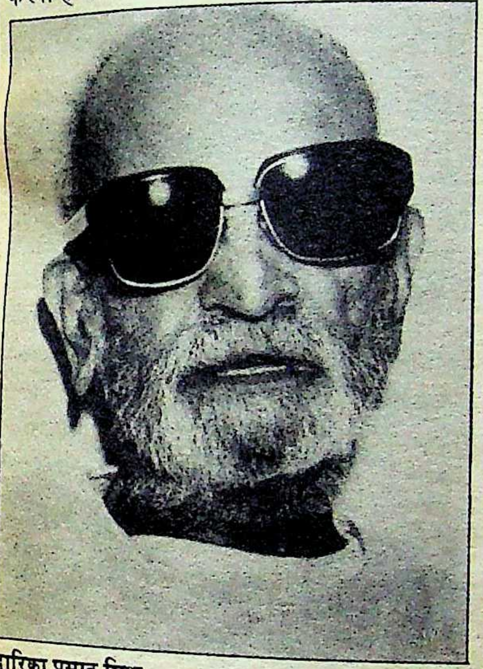

द्वारिका प्रसाद मिश्र

दीक्षित राजीव गांधी के काफी विश्वासपात्र हैं और त्रिपाठी अब भी वीर बहादुर सिंह के साथ इस कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश राजीव गांधी के हाथ से न निकले।

चालाक तिकड़ी : कुछ सांसद, आश्चर्य की बात है कि जिनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कमलापति त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित व द्वारिका प्रसाद मिश्र (जो अचानक दिल्ली पहुंचे थे) की चालाक तिकड़ी राजीव गांधी को अपने कब्जे में लेने के लिए एकजुट हो गयी है। इन लोगों का सोचना है कि बोफोर्स या ऐसे ही किसी अन्य घोटाले के कारण राजीव गांधी को हटना पड़ सकता है। यदि ऐसी स्थिति आती है, तो पार्टी पर नियंत्रण होने के नाते ये लोग अपने किसी प्रत्याशी की ताजपोशी करने में कामयाब हो सकते हैं। नरसिम्हा राव और कृष्ण चंद्र पंत का नाम भी लिया जाने लगा है। जो नेता सोशलिस्ट फोरम का विरोध कर रहे हैं (इनमें ज्यादातर ब्राह्मण हैं,) वे मानते हैं कि जो ब्राह्मण नेता राजीव गांधी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। पं० कमलापति त्रिपाठी चाहते हैं कि उनके सुपुत्र (लोकपति त्रिपाठी) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिये जायें, द्वारिका प्रसाद मिश्र चाहते हैं कि हाल में संयुक्त राष्ट्र से लौटे उनके पुत्र, ब्रजेश को राजनीति में प्रवेश मिल जाये और दीक्षित की आकांक्षा है कि उनकी पुत्रवधू शीला दीक्षित की किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में पदोन्नति कर दी जाये।

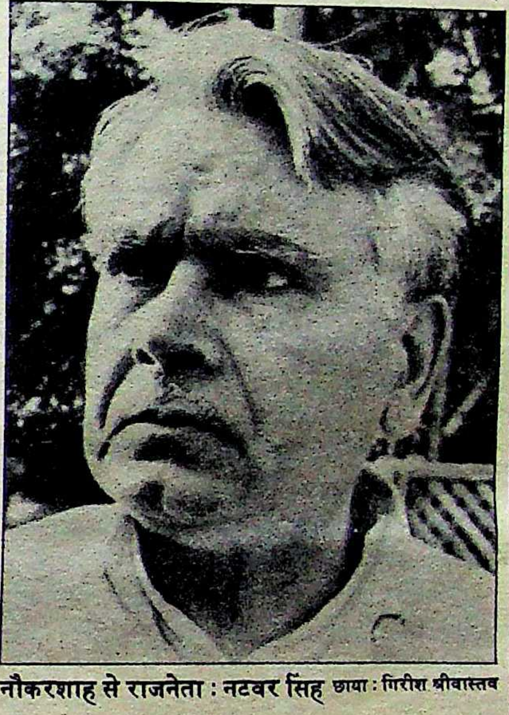

नौकरशाह से राजनेता : नटवर सिंह छाया : गिरीश श्रीवास्तव

हालांकि द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 'माया' को जो बताया है (देखिए साक्षात्कार) उससे ऐसा नहीं लगता कि उनका अपना कोई स्वार्थ है। दूसरी ओर दीक्षित भी राजीव गांधी के काफी विश्वासपात्र हैं और त्रिपाठी अब भी वीर बहादुर सिंह के साथ इस कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश राजीव गांधी

छाया : आर० बसु

"सामंती तत्वों ने कांग्रेस की मध्य वाम छवि को धूमिल कर दिया है, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए हैं। हम सभी निर्धनों के पक्षधर हो सकते हैं, जब उस वर्ग का प्रतिनिधित्व उभर कर आये। कहावत है, "जाके पैर न फटी बेवाई, ते का जाने पीर परायी" ऐसी स्थिति में सामंतों को वस्तुतः अपने ठाठ-बाट छोड़कर आम जनता से जुड़ना होगा। सामंतवाद एक व्यवस्था है। यह एक मानसिक दृष्टिकोण है। जो भी पूंजीपति-समर्थक, गरीब-विरोधी है, इसी श्रेणी में आता है। वे छोटे लोग हैं, जिन्हें इसमें ब्राह्मण-ठाकुर दिखायी पड़ते हैं। मैं निःसंदेह ऐसे किसी विशेष व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, किंतु मैं हर उस व्यक्ति का विरोध करूंगा जो पार्टी की स्वीकृत नीतियों का पालन नहीं करता।"

[illegible]

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

"नव-सामंत आज पुरानों से कहीं अधिक धनी हैं। उन पर और उनकी गतिविधियों पर रोक और नियंत्रण जरूरी है। यदि आप स्थिति का अध्ययन करें, तो पायेंगे कि ऐसे असंख्य परिवार उभरे हैं जो केवल राजनीति के माध्यम से गत ४० वर्षों में धनी हुए हैं। जनता का प्रेम और सद्भाव ही हमारी एकमात्र पूंजी है। जो सद्भाव हमें प्राप्त है, उसकी वजह जनता के प्रति हमारी सेवा-सहानुभूति है। मुझे पता नहीं कि उ०प्र० में स्थिति इससे भिन्न रही है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है, अधिकाधिक सिंचाई परियोजनाओं पर अमल, जिससे किसान धनी और खुशहाल हों। मुझे गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सभी संभावित परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। लोग यह नहीं देख रहे हैं कि राजीव गांधी, पार्टी और देश का भला कैसे हो। उनकी रुचि मात्र व्यक्तिगत लाभ पाने में है।"

—शिवेंद्र बहादुर सिंह

के हाथ से न निकले।

पंडितजी को झटका : हालांकि हाल में वाराणसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, उससे पंडित कमलापति त्रिपाठी को झटका लगा है। पंडितजी विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनसभा के दिन से पहले कुछ दिनों से काशी में ही पड़ाव डाले हुए थे। इस विशाल जनसभा से पंडितजी के विरोधियों को अच्छा मौका मिल गया है। वे लोग पंडितजी पर शक कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सार्वजनिक रूप से, आलोचना करके त्रिपाठी राजीव गांधी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उनका तर्क है कि वाराणसी में भारी भीड़ का जुटना और विश्वनाथ प्रताप सिंह को 'राजर्षि' (हालांकि इस पर काफी विवाद है—देखिए, इसी अंक में बनारस में वी०पी० सिंह की जनसभा की रपट) की उपाधि का मिलना, बिना पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रच्छन्न समर्थन के संभव नहीं हो सकता था। जाहिर है, शंका के बीज बोने का खेल पूरे जोरों पर है और यह खेल राजीव गांधी को और अधिक विभ्रम में डालेगा, उनकी स्थिति और संकटमय बनायेगा। ठाकुर खेमे का कहना है कि राजीव गांधी की हालत जितनी खराब होगी, त्रिपाठियों और रायों के उतने ही मजे होंगे।

हालांकि पंडित कमलापति त्रिपाठी पर ऐसे आरोप और शंकाएं तथा राजाओं को हटाने के पीछे कथित इरादे अतिरंजित हैं, लेकिन इस समय अनिश्चितता और संशय का जो माहौल है, उसमें इन आरोपों का कांग्रेस पर घातक असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा डर तो यह है कि राजीव गांधी के जो कुछ दोस्त और हितैषी बचे हैं, उनसे भी वह अलग-थलग हो सकते हैं। पार्टी के केंद्रीय ढांचे में इस समय जो चुगली-चांटा दिखायी पड़ता है, उससे शिवेंद्र बहादुर सिंह जैसे राजीव गांधी के दोस्तों का 'दम घुटने' लगा है। उनका कहना है कि जिस ढंग से सामंतवाद के खिलाफ मुहिम चलायी जा रही है, उसका आधार किसी व्यक्ति के जन्म को बनाया जा रहा है। शिवेंद्र बहादुर सिंह कहते हैं, 'मैं इसका संबंध जन्म से नहीं कर्म से मानता हूं।" खैरागढ़ के भूतपूर्व शासक और वर्तमान सांसद शिवेंद्र बहादुर सिंह राजीव गांधी के दून-सखा हैं। उन्होंने 'माया' को बताया, "हमने अपने लोगों और देश की सेवा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। हाल में खड़ी हुई विरोधियों की फौज में ऐसे कितने लोग हैं, जिन्होंने एक परिवार से तीन लोगों स्वयं, पिता एवं माता—को पार्टी और सरकार की सेवा में अर्पित किया हो ? वे कितना कर देते हैं और उनका १९४७ में कितना 'बैंक बैलेंस' था और अब कितना है ?"

सिंह का मानना है कि इस समय जो लोग सामंतवाद के खिलाफ मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं,

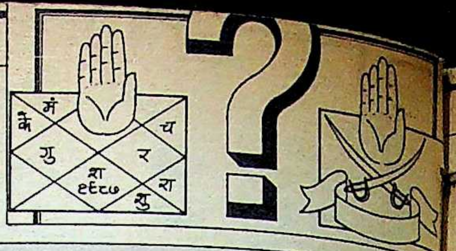

साक्षात्कार/

कल्पनाथ राय

फरमान जारी हो, अंग्रेज भक्त राजा कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते

माया : एक बार फिर कांग्रेस के अंदर राजा-रजवाड़ों व सामंती तत्वों के विरुद्ध मुहिम तेज हुई है। इसके पीछे क्या मकसद है ?

राय : कांग्रेस के अंदर जो संघर्ष छिड़ा है, यह आजादी की लड़ाई लड़नेवाले स्वतंत्रता-सेनानी एवं आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देनेवाले सामंतों के बीच है। यह लड़ाई समाजवादी ताकतों एवं सामंती ताकतों के मध्य लोकतंत्र को कायम रखनेवाले तथा राजतंत्र को वापस लानेवाली शक्तियों के बीच है। आज सी०आई०ए० के इशारे पर दुनिया की साम्राज्यवादी शक्तियों का एजेंट बनकर विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत में लोकतंत्र को मिटाकर राजतंत्र वापस लाना चाहते हैं। इस पूरी योजना में अंग्रेजों का साथ देनेवाले सारे राजे-रजवाड़े उनके साथ शामिल हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि—बोफोर्स एक बहाना है, राजतंत्र को लाना है, लोकतंत्र मिटाना है, यही विश्वनाथ का गाना है।

माया : लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह तो अब कांग्रेस के अंदर नहीं हैं। फिर आज कांग्रेस के अंदर किन सामंती तत्वों को हटाने की बात की जा रही है ?

राय : आजादी की लड़ाई लड़नेवालों का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि आज भी वे दो लाख की संख्या में जिंदा हैं और उनकी जिंदगी में ही अंग्रेजों का साथ देनेवाले राजा-रजवाड़े गद्दी के मालिक बने बैठे हैं।

माया : क्या आप स्पष्ट करेंगे कि आज गद्दी पर बैठे हुए किन राजा-रजवाड़ों के लिए आप यह कह रहे हैं।

राय : मैं किसी एक की बात नहीं कहता हूं। आपको इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि पंडित नेहरू ने १७ वर्ष की अपनी हुकूमत में एक भी राजा को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। श्रीमती गांधी ने पहली बार दो राजाओं को कैबिनेट मंत्री बनाया और दोनों ने ही उन्हें धोखा दिया। (राजा कर्ण सिंह, तथा राजा दिनेश सिंह), श्रीमती गांधी द्वारा बनाये गये

ये दोनों ही केन्द्रीय मंत्री श्रीमती गांधी की पराजय के बाद जनता काल में कांग्रेस छोड़कर चले गये थे, फिर जब इंदिरा गांधी तक को इन राजा-रजवाड़ों ने धोखा दे दिया, तो राजीव गांधी क्या हैं? राजीव गांधी को तो ये राजे-रजवाड़े अपने-अपने घरों में षड्यंत्र करते समय दुधमुंहा बच्चा कहते हैं।

माया : ऐसी स्थिति में राजीव गांधी को क्या करना चाहिए?

राय : जिस तरह श्रीमती गांधी ने राजाओं का प्रिवीपर्स समाप्त किया था, आज उसी तरह राजीव गांधी को सभी अंगेजों का साथ देनेवाले राजाओं को कांग्रेस की सदस्यता से ही वंचित कर देना चाहिए। ए०आई०सी०सी० की तरफ से फौरन एक फरमान जारी होना चाहिए कि अंग्रेजों का साथ देनेवाले जो भी रजवाड़े हैं, वे कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। तभी कांग्रेस समाजवाद की स्थापना का हथियार बन सकेगी।

माया : अंग्रेजों का साथ देने के आरोप के जवाब में कांग्रेस में मौजूद कई राजाओं ने यह कहा है कि संभव है, उनके बाप-दादाओं ने ऐसा किया हो, पर उसके आधार पर उन्हें क्यों लांछित किया जाये जो आजादी की लड़ाई के बाद ही बड़े हुए हैं तथा जब से राजनीति में आये, तब से कांग्रेस में हैं। इस संदर्भ में अर्जुन सिंह ने यहां तक कहा है कि यह आरोप वही लोग लगा सकते हैं जो अपने मां-बाप का खुद चुनाव करने में सक्षम हों।

राय : राष्ट्रद्रोह व जनघात करनेवाले ये राजे-रजवाड़े जब तक अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जनसेवा का ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत करते, तब तक इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके लिए इन्हें पहले सब त्यागकर वर्षों-वर्षों जनता के सेवक के रूप में तपस्या करनी पड़ेगी। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और फिर उसके बाद अमेठी के विधायक राजकुमार संजय सिंह ने जिस तरह राजीव गांधी की पीठ पर छुरा भोंका, उनकी गद्दारी के सामने शर्म भी लज्जित हो उठी। इसके बाद भी अब क्या कुछ देखने को रह गया है कि मीठी बोली बोलनेवाले ये विनम्र राजा-रजवाड़े कितने खतरनाक और जहरीले होते हैं। षड्यंत्र करना इन्होंने अपनी विरासत में पाया है।

माया : क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अन्दर आज मौजूद ये राजा-रजवाड़े राजीव गांधी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। यदि हां, तो क्या आप इसका सबूत पेश कर सकते हैं।

राय : भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने खुद मुझसे कहा था कि राजीव गांधी मंत्रिमंडल के सात मंत्रियों ने उनसे राजीव सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा है। मैंने यह बात २८ मई को राजीव गांधी को बतायी कि ऐसा राष्ट्रपति ने मुझसे कहा है। यह गंभीर मामला है। आप ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखें और उन्हें उचित समय पर निकाल बाहर करें। राष्ट्रपति ने मुझसे यह भी कहा था कि उन सात में तीन मंत्री तो सत्ता से बाहर हो चुके हैं, पर चार अभी अंदर हैं। इसके बाद भी क्या किसी सबूत की जरूरत रह जाती है?

माया : क्या आप उन चार मंत्रियों के नाम बतायेंगे, जिन्होंने ज्ञानीजी से राजीव गांधी को बर्खास्त करने के लिए कहा था जो आज भी राजीव मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

राय : मैं उनके नाम राजीव गांधी को बता चुका हूं।

माया : लेकिन उनके नाम आपने हमें तो नहीं बताये।

राय : समय आने पर मैं वे नाम आपको भी बताऊंगा, लेकिन अभी स्थिति बेहद नाजुक है। इस समय इन चारों मंत्रियों का नाम छापना कांग्रेस के लिए हितकर नहीं होगा।

माया : क्या आपको विश्वास है कि राजीव गांधी राजा-रजवाड़ों से मुक्त हो पायेंगे? क्या उन चार मंत्रियों को वह मंत्रिमंडल के बाहर कर पायेंगे, जिनकी ओर आपने अभी इशारा किया है? यदि यह आप द्वारा दी गयी सूचना सच है और आप राजीव गांधी को मई में ही इसके बारे में बता चुके हैं, तो उन्होंने अब तक उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल के बाहर क्यों नहीं निकाला? क्या कोई मजबूरी है?

राय : मुझे विश्वास है, दूध के जले राजीव गांधी मट्ठा फूंक-फूंककर पियेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा संजय सिंह के दो उदाहरण ही सबक लेने के लिए काफी हैं। इतिहास एवं नियति ने उन पर ऐतिहासिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं या तो हिंदुस्तान राजीव गांधी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगा तथा एटामिक बमों से लैस अंधेरे के काले दरिया में डूबी इंसानियत एवं दुनिया को बचाने की भूमिका अदा करेगा या भारत बिखरकर टूट जायेगा। आनेवाली जिम्मेदारियों को राजीव गांधी कैसे सफलतापूर्वक उठा पायेंगे यह बहुत कुछ उनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा या तो टूटता हुआ भारत शक्तिशाली होकर इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करेगा अन्यथा यदि बुद्धिमानी से कदम न उठाये गये, तो इक्कीसवीं शताब्दी से पहले ही भारत टूट जायेगा। शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में भारी उलट-पलट करना होगा। योजना बनाते समय जब गांधी के दरिद्र-नारायण की तस्वीर सामने होगी, तभी राजीव गांधी शक्तिशाली होंगे।

छाया : सुनील सक्सेना

"मैं एक सामंत नहीं हूं, क्योंकि मैं सामंतवाद के बाह्याडम्बर से मुक्त हूं। अधिकतर सत्ताधारी राजनीतिक सामंतों से भी गयाँ-गुजरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें अभिजात गुण होते ही नहीं। के०एन० सिंह और उनके संगी-साथी कुंठाग्रस्त लोग हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़कर और चापलूसी से पुनः सत्ता पाना चाहते हैं। वे अपने को अधिक वफादार साबित करने की भरपूर कोशिशों में जुटे हैं। उनके जीवन का लक्ष्य केवल सत्ता हथियाना है, भले ही इसके लिए उन्हें किसी के तलुए सहलाने पड़ें या किसी को गाली देनी पड़े। उन्हें यह सब करने में कोई हिचक नहीं। पिछले ४० साल में तो देश और समाज की छवि ही बदल गयी है।

ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गये
कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गये।"

—भानुप्रकाश सिंह

उनकी जांच हो, तो कलई खुल जायेगी। यद्यपि उन्होंने कमलापति त्रिपाठी और कल्पनाथ राय का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है। शिवेंद्र बहादुर सिंह जैसे राजीव के करीबी दोस्त एक ओर यह महसूस कर रहे हैं और दूसरी ओर कमलापति त्रिपाठी और कल्पनाथ राय जैसे लोग अंधाधुंध आरोप लगा रहे हैं कि राजा, राजीव के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यह स्थिति कोई शुभ नहीं है। इस स्थिति में पार्टी को लंबे समय तक एक बनाये रखना संभव नहीं दिखता। हकीकत तो यह है कि यदि तथाकथित सामंतों को पार्टी से निकाल दिया जाये तो वह स्थिति राजीव गांधी के लिए एक राजनीतिक तबाही का कारण हो सकती है। उनको अरुण सिंह की छुट्टी करनी होगी, जिन्होंने मंत्री-पद छोड़ा है, लेकिन एक शब्द भी राजीव गांधी के खिलाफ नहीं कहा है। दिनेश सिंह ने फेयर-फैक्स के मामले में राजीव गांधी के लिए वी०पी० सिंह से लोहा लिया है। माधव राव सिंधिया भी दबाव में हैं, क्योंकि राजीव के पक्षधर एक अंग्रेजी अखबार ने उनके कथित विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन (फेरा) का वह किस्सा दुबारा प्रकाशित किया है जो एक साल पहले 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में छप चुका है। उस समय वी०पी० सिंह वित्तमंत्री थे और उन्हें कहा गया था कि वह सिंधिया के बचाव में बोलें। अब सिंधिया पर फिर से हुए आक्रमण के पीछे राजीव गांधी का इशारा माना जा रहा है, जिससे उनको निकालने के लिए जमीन तैयार की जा सके। बहरहाल, यदि सिंधिया को निकाला जाता है, तो राजीव गांधी को एक आदमी ढूंढ़ना होगा जो ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी को हरा सके। इसके अतिरिक्त एक खतरा और भी है—वह है कांग्रेस के खिलाफ मां-बेटे का समीकरण। इसके साथ अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, और शुक्ला-बंधु भी यदि कांग्रेस के खिलाफ हों, तो स्थिति क्या होगी, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या इस तरह के समीकरण से सफलतापूर्वक लड़ने की क्षमता मिश्राओं और त्रिपाठियों में है?

बहाना : असलियत तो यह है कि यह सब सत्ता की लड़ाई है जो ठाकुर-ब्राह्मण संघर्ष के रूप में लड़ी जा रही है और जो राजीव गांधी के लिए बहुत महंगी सिद्ध होगी। जहां तक सिद्धांतों की बात है, इस संघर्ष से सिद्धांतों का कोई संबंध नहीं है। वी०पी० सिंह और संजय सिंह की साख खराब करने के लिए पंडित कमलापति त्रिपाठी को राजाओं के खिलाफ बोलने की अनुमति चाहे राजीव गांधी देते रहें और चाहे पार्टी को समाजवादी मुद्रा देने के लिए गाडगिल और गणेश को भी सोशलिस्ट फोरम बनाने दें, लेकिन उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपाठी और गणेश उनके कितने हितैपी

उत्तर प्रदेश के राजा-महाराजा

विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद संजय सिंह के विद्रोह ने ही इस आरोप को जन्म दिया है कि राजा-महाराजा राजीव गांधी की सत्ता छीनने पर आमादा हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यह प्रदेश भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। स्वयं राजीव गांधी का चुनाव क्षेत्र अमेठी—भी उत्तर प्रदेश में है। अतः सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति—खासकर इंका की राजनीति में भूतपूर्व राजघरानों का दखल कितना है? उत्तर प्रदेश में राजा-महाराजाओं और भूतपूर्व ताल्लुकेदारों की संख्या पांच सौ के लगभग है, जिनमें ४० रजवाड़े कांग्रेस से जुड़े हैं। इन राजघरानों से सम्बद्ध कुछ प्रमुख नेता और उनका झुकाव इस प्रकार है :

दिनेश सिंह

कालाकांकर राज्य का स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए मोतीलाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू का कालाकांकर राज्य से घनिष्ठ संबंध रहा। इन्हीं संबंधों का लाभ दिनेश सिंह को मिला। १९६६ में श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो दिनेश सिंह कांग्रेस की एक खास हस्ती बन गये थे। कांग्रेस में उनकी इस अहमियत से उत्तर प्रदेश के अन्य रजवाड़े भी प्रभावित थे, लेकिन १९७१ में फूलपुर (इलाहाबाद) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से राजा मांडा को लोकसभा में लाने के बाद दिनेश सिंह की अहमियत छीजने लगी। यही कारण माना जाता है कि फेयरफैक्स के मामले में वी०पी० सिंह से लोहा लेनेवालों में दिनेश सिंह पहले व्यक्ति थे। शायद दिनेश सिंह को उम्मीद थी कि इस टक्कर से उनको कोई लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि दिनेश सिंह, श्रीमती गांधी की हार के बाद जनता पार्टी में चले गये थे, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद पुनः कांग्रेस में आ गये। राजाओं के खिलाफ यदि अभियान तेज हुआ, तो दिनेश सिंह का रुख क्या होगा, कहा नहीं जा सकता।

राजा अजीत प्रताप सिंह

राजा दिनेश सिंह के बाद उत्तर प्रदेश की इंका राजनीति में दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति प्रतापगढ़ के राजा अजीत प्रताप सिंह हैं। वह स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से होते हुए १९६७ के बाद राजा दिनेश सिंह के प्रयत्नों से कांग्रेस में शामिल हुए थे। विचित्र संयोग है कि १९८० के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से इंका के टिकट पर अजीत प्रताप सिंह, राजा दिनेश सिंह (उस समय जनता पार्टी में) को ही हराकर चुने गये थे। फिर १९८४ के चुनाव में राजा मांडा और नारायण दत्त तिवारी की कड़ी पैरवी के बावजूद दिल्ली दरबार ने अजीत प्रताप का टिकट काटकर दिनेश सिंह को उम्मीदवार बना दिया। बाद में राजा मांडा के प्रयास से ही अजीत प्रताप विधान परिषद के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश में आबकारी मंत्री बने। वर्ष १९८७ में पट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रोफेसर वासुदेव सिंह के निधन से रिक्त हुई सीट पर राजा मांडा के प्रयास से ही अजीत प्रताप सिंह को टिकट मिला और वह भारी बहुमत से विजयी हुए। अजीत प्रताप के पुत्र अरुण प्रताप सिंह भी पहली बार इंका के टिकट से गैसडी (गोंडा) निर्वाचन क्षेत्र से मार्च १९८५ के चुनाव में विधानसभा के लिए विजयी हुए। अजीत प्रताप सिंह आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। उनकी और उनके पुत्र की सहानुभूति राजा मांडा के साथ मानी जाती है।

राजा अमीर मोहम्मद खां

सीतापुर की महमूदाबाद रियासत के भूतपूर्व राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, पूर्वरक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह के साढ़ू हैं। राजा अमीर मोहम्मद को पिछले विधानसभा

चुनाव में अम्मार रिजवी का टिकट काट कर इंका ने महमूदाबाद से लड़ाया था, जहां से वह भारी मतों से जीते। राजा महमूदाबाद की नागरिकता के सवाल को लेकर पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में काफी हंगामा हुआ था। वह व्यक्तिगत रूप से राजा मांडा के समर्थक हैं।

आनंद सिंह

मनकापुर रियासत के राजा और इंका सांसद आनंद सिंह, रिश्ते से राजा मांडा के समधी हैं। गोंडा तथा आसपास के जिलों में आनंद सिंह का अच्छा प्रभाव है। वर्ष १९७१, १९८० और १९८५ में वह गोंडा संसदीय क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी हुए थे। दिल्ली दरबार लगातार इस कोशिश में है कि राजा मनकापुर किसी भी हालत में राजा मांडा के साथ न जायें, क्योंकि पार्टी से उनके मुंह मोड़ने का अर्थ होगा एक दर्जन से अधिक विधायकों से हाथ धोना। लेकिन इस सबके बावजूद आनंद सिंह पूरी तरह राजा मांडा के साथ हैं।

रणजीत सिंह जूदेव

झांसी जिले की समथर स्टेट के राजकुमार रणजीत सिंह जूदेव १९८०-८५ के दौरान सत्तारूढ़ दल में संजय सिंह जैसी हैसियत रखते थे, लेकिन १९८५ के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद वह आजकल थोड़ा ठंडे पड़े हुए हैं। वर्तमान समय में जूदेव, वीर बहादुर सिंह के खास सलाहकार माने जाते हैं। इस कारण वीर बहादुर सिंह शायद ही यह पसंद करेंगे कि रजवाड़ों के खिलाफ अभियान के शिकार जूदेव भी हों।

राजा मोहन सिंह

भूतपूर्व तिलोई (रायबरेली) स्टेट के राजा मोहन सिंह का विधानसभा क्षेत्र, अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है। इसलिए राजा मोहन सिंह की सीधी पहुंच दिल्ली दरबार तक है। तिलोई स्टेट १९६७ से पूर्व तक जनसंघी थी। १९७७ के चुनाव में जब अमेठी से संजय गांधी और रायबरेली से इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गयी थीं, तो मोहन सिंह, इंका के टिकट पर विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे थे। अमेठी संसदीय क्षेत्र में आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों में किसी एक का प्रतिनिधित्व कोई मुस्लिम करे, यह मांग उठते ही इंका ने १९८० के चुनाव में राजा मोहन सिंह का टिकट काटकर हाजी वसीम को उम्मीदवार बना दिया। टिकट कटने से राजा मोहन सिंह नाराज न हों, इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग का अध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दे दिया गया। मोहन सिंह की निष्ठा अभी तक राजीव गांधी में ही है।

राजा रुद्र प्रताप सिंह

अमेठी संसदीय क्षेत्र की ही एक दूसरी रियासत जामों के भूतपूर्व राजा रुद्र प्रताप सिंह राज्यसभा में इंका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली दरबार ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (पी०सी०एफ०) का चेयरमैन भी बना दिया था, लेकिन डेढ़ वर्ष पूर्व उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। रुद्र प्रताप सिंह तो अभी तक पूरी तरह राजीव गांधी के साथ हैं, किंतु उनके भाई तथा जामों के छोटे राजा लाल साहब, राजा मांडा के साथ हैं। वे कहते हैं, "राजा की आंधी के आगे, अब इंका ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी।"

श्रीमती इंद्र मोहिनी

मुरादाबाद जिले की सहसपुर, बिलारी स्टेट की राजकुमारी इंद्रमोहिनी का भी इंका-राजनीति में काफी दखल है। यही वजह है कि वह जहां विधान परिषद की सदस्य हैं, वहीं चुनाव में अपनी पुत्री रीना कुमारी को भी इंका का टिकट दिलवाकर विधानसभा में पहुंचवा दिया है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में श्रीमती इंद्रमोहिनी तन-मन-धन से नारायण दत्त तिवारी के साथ हैं।

—अजय कुमार

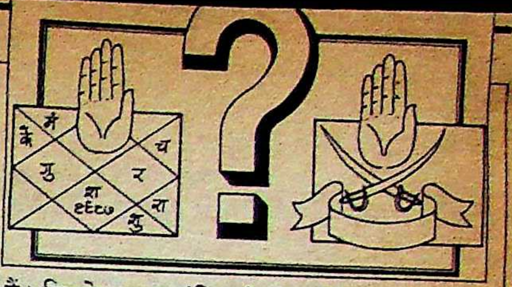

हैं। पिछले साल पंडितजी ने जो खत लिखे थे, उनका मजमून क्या राजीव गांधी भूल गये? क्या यह बात भी उनको किसी ने नहीं बतायी कि आर० के० गणेश वहीं है जो श्रीमती गांधी के बुरे दिनों में साथ छोड़करचले गये थे। जाहिर है ऐसे लोग इतने उदार नहीं हैं कि राजीव गांधी की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आये हों।

भानुप्रकाश सिंह अपना गुस्सा उगलते हुए कहते हैं, "जो मर गया ४० साल पहले, जिसकी लाश भी दफना दी गयी है, उसकी कब्र पर खड़े होकर ये उलटे मंत्र पढ़ रहे हैं—इस भय से कि कहीं वह जिंदा होकर इनके हाथ से सत्ता न छीन ले।" सिंह का मानना है कि सभी क्षत्रिय राजीव गांधी के साथ हैं। उनको इसलिए राजीव से अलग करने का षड्यंत्र हो रहा है, जिससे राजीव गांधी से सत्ता छीनी जा सके। आश्चर्य की बात है कि पी०एन० सुकुल जैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी इसी तरह का मत व्यक्त कर रहे हैं, "दरअसल सामंत-विरोधी मुहिम चला कर जो अंधाधुंध आरोप लगाये जा रहे हैं, उससे पार्टी को बेहद क्षति पहुंच रही है। इससे उन लोगों को काटा जा रहा है जो नेतृत्व में अटूट आस्था रखते हैं।" संसदीय दल के कोषाध्यक्ष सुकुल का दावा है कि राजीव गांधी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह उन लोगों के साथ हैं, जो राजाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वह कहते हैं, "यह सही है कि ज्यादातर रजवाड़ों का हमारे स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन नहीं मिला, लेकिन आज स्थिति बिलकुल अलग है। यह कहना गलत होगा कि सभी राजा राष्ट्र-विरोधी हैं। उसी तरह से यह कहना भी सही नहीं है कि सारे ब्राह्मण राष्ट्रवादी और राजीव-समर्थक हैं।" उनकी इस बात में दम है। आखिर त्रिपाठियों, रायों या शुक्लाओं तथा जगन्नाथ मिश्राओं की स्थिति क्या है। यदि कुल मिलाकर देखा जाये तो यह सारा शोर-गुल व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों से प्रेरित है।

आज भूतपूर्व राजाओं का पार्टी के ढांचे में प्रमुख स्थान है और उनमें से काफी राजीव गांधी के भी करीब हैं। १९८० में संजय गांधी ने भी ऐसे कुछ लोगों को चुना था, जिससे कि जनता पार्टी के खिलाफ जीत हासिल की जा सके। इसी कारण पहली दफा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ब्राह्मणों से कुछ ज्यादा ठाकुर चुनकर के पहुंचे थे। अब यह कहना निरर्थक है कि उनका इसलिए सफाया कर दिया जाये, क्योंकि वी०पी० सिंह और संजय सिंह ने बगावत कर दी। आखिर अरुण नेहरू ने भी ऐसा ही किया है, जबकि वह ब्राह्मण भी हैं और राजीव गांधी के रिश्तेदार भी। गुंडूराव और प्रणब मुखर्जी क्या हैं, श्रीपति मिश्रा और ए०पी० शर्मा क्या हैं? और यह भी कि उस समय पंडित कमलापति त्रिपाठी ने भी इनका पक्ष लिया था। ये सभी ब्राह्मण

दावणगेरे

फ़ैशन फ़ैब्रिक्स

सोनी टेरीन* –आधुनिक और
आरामदायक फ़ैब्रिक में
आकर्षक रंगों में मिलें,
खूबसूरती से संवरें
और ढलें.
और कीमत...
आपकी मनचाही.

साथ ही उपलब्ध

- सूटिंग्स • शर्टिंग्स
- साड़ियां
- कैम्ब्रिक
- टू × टू रूबिया
- टर्किश टॉवेल्स

T/8788/A/HIN

दि दावणगेरे कॉटन मिल्स लिमिटेड

हनुमानथप्पा बिल्डिंग्स, चित्रदुर्गा रोड, दावणगेरे-५७७ ००२.
शोरूमः कावेरी भवन, बंगलौर-५६० ००९.
दाजीबन पेठ, हुबली-५८० ०२०. चित्रदुर्गा रोड, दावणगेरे-५७७ ००२.

* टेरीन काफ़ी का ट्रेडमार्क है

मं
य
कें
गु
र
श्रा
शु
रा
१९८८

ही तो हैं। जबकि माधव सिंह सोलंकी ठाकुर हैं, लेकिन गुजरात से उनको निकाले जाने के बावजूद वह हमेशा राजीव गांधी के प्रति वफादार हैं लेकिन त्रिपाठी, के०आर० गणेश, गाडगिल, के० एन० सिंह जो अब राजीव गांधी के रक्षक बनने का दावा कर रहे हैं, समय-समय पर बेवफा सिद्ध हुए हैं। यद्यपि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने जो आरोप लगाये हैं, उन पर राजीव गांधी ने चुप रहना शायद इसीलिए वाजिब समझा है, जिससे कहीं पार्टी में दो फाड़ होने की स्थिति उत्पन्न न हो। उनको उम्मीद है कि वक्त के साथ यह सारा विवाद थम जायेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आखिर त्रिपाठीजी कब तक अपने सुपुत्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसी तरह कल्पनाथ राय कब तक मंत्री बनने का इंतजार करते रहेंगे? और यदि गाडगिल को सत्ता में हिस्सा नहीं मिला, तो वह भी कब तक राजीव गांधी के समर्थन में गुहार लगाते रहेंगे? सोशलिस्ट फोरम के मंच से उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें यह कहा गया है कि १९८५ से जो नीतियां अपनायी जा रही हैं, वे समाजवाद-विरोधी, नेहरू-विरोधी और गरीब-विरोधी है। उन्होंने परोक्ष रूप से वी०पी० सिंह पर इसका दोष डाला है, लेकिन वी०पी० सिंह का तो अब कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं। सातवें दशक में भी सोशलिस्ट फोरम खड़ा हुआ था, लेकिन जब श्रीमती गांधी ने देखा कि वह एक दबाव-गुट के रूप में उभर रहा है, तो उन्होंने इसको ढहा दिया था। लेकिन उस समय श्रीमती गांधी बहुत सशक्त थीं। अब राजीव गांधी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह ऐसा कदम उठायें, जिससे और ज्यादा दुश्मन पैदा हों। लेकिन स्थिति ऐसी आ सकती है, जब हमले का रुख राजीव गांधी की ओर हो सकता है। जो लोग वी०पी० सिंह के ऊपर समाजवाद-विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि कल वही लोग सीधे-सीधे राजीव गांधी पर हमला बोलने लगें, क्योंकि आखिरकार ये सारी नीतियां राजीव गांधी के नेतृत्व में लागू हुई थीं। जाहिर है जो लोग स्वार्थवश राजाओं के खिलाफ जेहाद छेड़े हुए हैं, वे लोग न तो समाजवाद ला सकते हैं और न राजीव गांधी की स्थिति मजबूत कर सकते हैं। खतरा तो यह है कि इससे राजीव गांधी की हैसियत एक जाति विशेष के नेता के रूप में सिकुड़ सकती है। यह राजीव गांधी के साथ एक प्रकार का अन्याय होगा। क्योंकि सही माने में देखा जाये, तो जातिवादी तो दूर, वह पारंपरिक दृष्टि से धर्म विशेष पर आचरण करने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। उनका लालन-पालन जिस परिवेश में हुआ है, उसको देखते हुए उनकी छवि को किसी जाति या धर्म के चौखटे में आबद्ध नहीं किया जा सकता।

बहरहाल, इसका मतलब यह नहीं है कि भूतपूर्व राजा-महाराजा पार्टी के लिए अपरिहार्य हैं। क्योंकि भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को इस समय जो अहमियत मिली हुई है, वह उनकी विरासत के कारण नहीं मिली हुई है। इस अहमियत के पीछे पार्टी की शक्ति है। जहां सामंतवाद का सवाल है, राजीव गांधी को असली खतरा नव सामंतों से है जो सत्ता, भ्रष्टाचार और चापलूसी से पनपे हैं। ऐसे लोगों की जीवन शैली उन राजा-महाराजाओं से कम नहीं है, जिनके महल अब जर्जरित हैं और जो सामान्य लोगों की तरह व्यापार और अन्य उद्योगों में लग गये हैं। ये भूतपूर्व राजा अच्छी तरह जानते हैं कि अब उनका अस्तित्व आम जनता और राजीव गांधी के समर्थन पर निर्भर है—उनके खास घराने में पैदा होने से न सत्ता मिलनेवाली है और न हैसियत।

मूल सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए कौन से 'सामंत' घातक हैं—पुराने राजा-महाराजा या नवोदित सामंत? के०सी० पंत, सुनील शास्त्री, वसंत दादा, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, मीरा कुमार, कृष्णा साही या उन जैसे अन्य लोग जो राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए नव सामंती मानासिकता में जीते हैं—उनका क्या होगा?

—विजयदत्त, रंजना कक्कड़

राजा-सहयोगी या विरोधी ?

राजाओं के प्रिवीपर्स व खिताब श्रीमती गांधी ने अवश्य छीने, किंतु कारण शायद राजनीतिक-कूटनीतिक ही रहा होगा, क्योंकि राजाओं से व्यक्तिगत संबंध विच्छेद उन्होंने कभी नहीं किया। यही नहीं इन पूर्व शासकों में से अनेक को उन्होंने पार्टी और सत्ता की मूलधारा से जोड़ा, उभारा। कश्मीर के राजा कर्ण सिंह को युवावस्था में ही नये शासक वर्ग में शामिल करने का श्रेय श्रीमती गांधी को ही है। कालाकांकर के राजा दिनेश सिंह का शासन, सत्ता और श्रीमती गांधी पर जो प्रभाव था, वह बहुत दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा है। यहां तक कि 'राजा' विश्वनाथ प्रताप सिंह पर पहला बाण चलाने के लिए उनका उपयोग करने में राजीव गांधी भी नहीं चूके। उनका अभिप्राय शायद तलवार को तलवार से काटने का ही था। कालाकांकर और नेहरू परिवार के पुराने संबंधों को देखते हुए (श्री मोतीलाल नेहरू लखनऊ में सदैव कालाकांकर हाउस में ही ठहरते थे) यह उपयोग सैद्धांतिक रहा हो या नहीं, दोनों परिवारों की पारस्परिक निर्भरता और आत्मीयता का द्योतक अवश्य है।

श्रीमती गांधी के चरण कमलों में अन्य 'राजा' भी पनपे, बढ़े। अर्जुन सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक अभ्युदय भी श्रीमती गांधी के समय ही हुआ। पडरौना के सी०पी०एन० सिंह, नरसिंहगढ़ के भानु प्रकाशसिंह, मनकापुर के आनन्द प्रताप सिंह , बड़ौदा के फतेह सिंह राव, प्रतापगढ़ के अजीत प्रताप सिंह, गायकवाड़ के के०पी० सिंह देव (उड़ीसा), बीकानेर के डा० कर्णी सिंह, पटियाला के अमरिन्दर सिंह आदि पार्टी और सरकार में समय-समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

राजाओं से राज्य चलाने की नीति का श्री राजीव गांधी ने भी समर्थन किया। सर्वविदित है कि श्रीमती गांधी के कई सहयोगी 'राजा' [illegible] राजीव के दायें-बायें हाथ हो गये। एक ओर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर राजीव गांधी ने एक नये भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिये नीति परिवर्तन की नींव डाली, तो दूसरी ओर अर्जुन सिंह पर पंजाब की गुत्थी सुलझाने का भार। आज उन पर आक्षेपों की बौछार भले ही हो रही हो, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि दोनों ही राजीव गांधी के कार्य को निभाने में काफी सफल रहे।

माधवराव सिंधिया (ग्वालियर), नटवर सिंह (भरतपुर) और अरुण सिंह (कपूरथला) की गिनती श्री गांधी के अंतरंग मित्रों में होने के अतिरिक्त अत्यन्त कुशल मंत्रियों में भी है।

संसद पर नजर रखने वाले जाने-माने पत्रकार एस० विश्वम के अनुसार जिस कुशलता से बजट अधिवेशन के दौरान सरकार और स्वयं राजीव गांधी के बचाव में अरुण सिंह ने उल्लेखनीय और अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था, वह आसानी से देखने को नहीं मिलता। नटवर सिंह की भूमिका पहले विदेश विभाग में कार्यरत अधिकारी और बाद में विभाग में मंत्री के रूप में भी कुछ कम नहीं रही है। श्रीलंका से समझौते में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। माधव राव सिंधिया रेल मंत्रालय का कार्यभार जिस कुशलता से निभा रहे हैं, यह इसी से स्पष्ट हो जाता [illegible] है कि मंत्रिमंडल में अनगिनत फेरबदल के उपरान्त भी, उनका विभाग कभी बदला नहीं गया। खैरागढ़ के शिवेन्द्र बहादुर सिंह यद्यपि मंत्रालय से दूर रहे हैं, तो भी सरकार, पार्टी और व्यक्तिगत रूप से श्री गांधी के कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहे हैं। एक सांसद के रूप में जो कार्य और सेवा उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में की है उससे प्रेरणा यदि अन्य सांसद लें, तो भारतवर्ष का नक्शा बदल जायेगा। ■

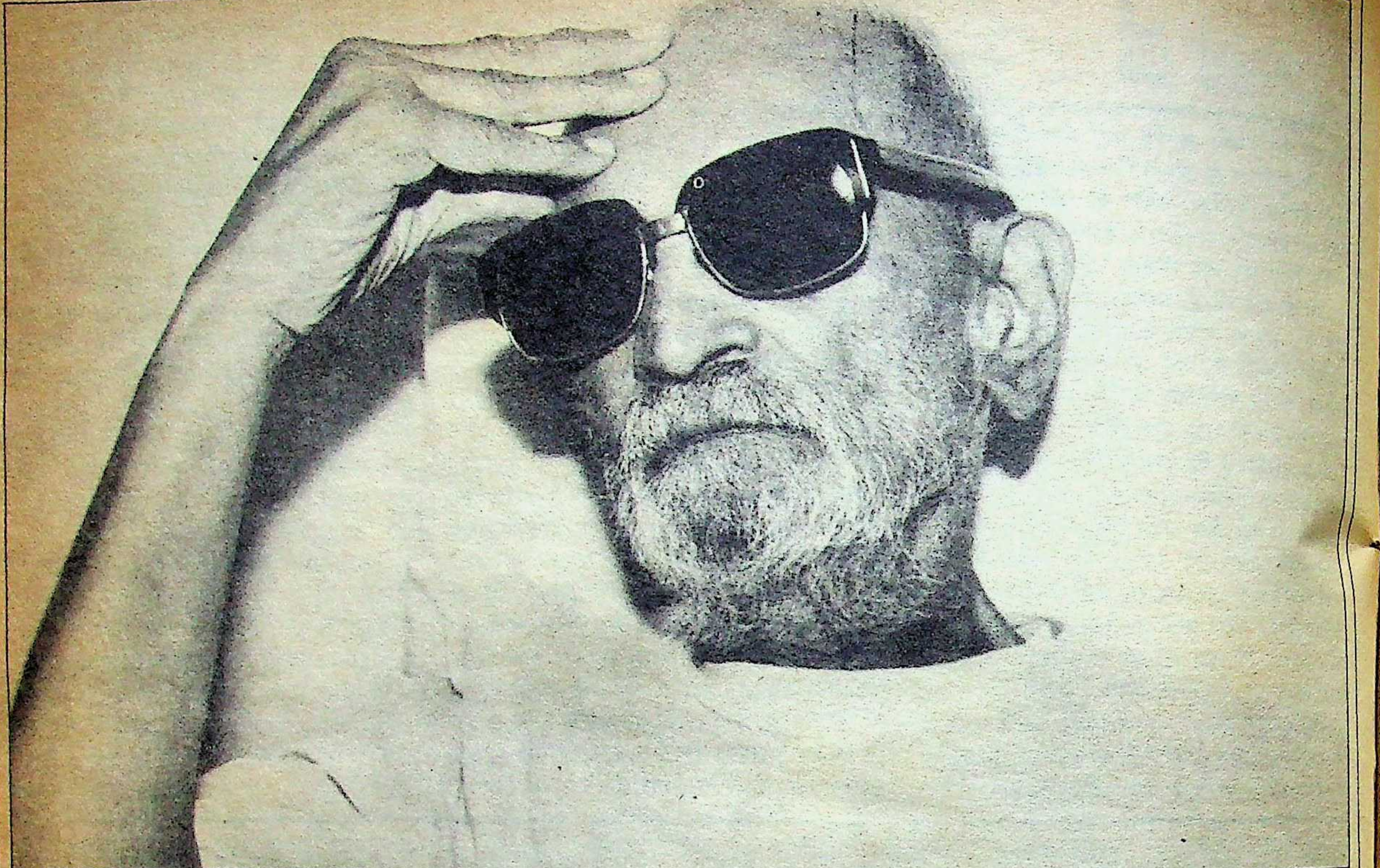

पं० द्वारिका प्रसाद मिश्र

जिनको (राजाओं) हमने खतम किया, उनको नयी जिंदगी दी जा रही है

वह सदा विशिष्ट रहे हैं। तब भी जब वह सत्ता में थे, शक्तिशाली थे और तब भी, जब वह सक्रिय राजनीति से अलग स्वैच्छिक संन्यास का जीवन बिता रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (१९६३-६७), फिर कांग्रेस संसदीय दल के सदस्य (१९६७-७१) रहे पं० द्वारिका प्रसाद मिश्र इंदिरा गांधी के आरंभिक दिनों से उनके प्रमुख सहायक और सलाहकार रहे हैं। १९६७ में श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में 'चाणक्य' कहे जाने वाले मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी और तब भी जब १९६९ में उन्होंने कांग्रेस का विभाजन करके अपना वर्चस्व स्थापित किया था। 'दादा' १९७२ में इंदिरा गांधी से सैद्धांतिक मतभेदों के बाद अपने शहर जबलपुर लौट गये थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर १९७७ में दिल्ली आये और उस गाढ़े समय में श्रीमती गांधी की सहायता की, जब कई प्रमुख कांग्रेसी नेता उन्हें पार्टी से निकालना चाहते थे। इसके बाद सक्रिय राजनीति में उन्होंने हाथ बहुत थोड़े समय के लिए डाला १९८३ में। अर्जुन सिंह से श्रीमती गांधी नाराज थीं। मिश्रजी दिल्ली आये, श्रीमती गांधी से बात की और उनकी नाराजगी दूर की। उसी वर्ष उनके नेत्रों की ज्योति चली गयी। द्वारिका प्रसाद मिश्र की विशिष्टता केवल उनकी विकट राजनीतिक प्रतिभा में ही नहीं रही है। वह कवि, इतिहासकार और संस्कृति के गहन अध्येता भी हैं। १९७२ में जबलपुर लौटने के बाद उन्होंने तीन खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी- 'लिविंग एन इरा', एक चर्चित महाकाव्य- कृष्णायन और ऐतिहासिक शोधपरक पुस्तक- 'प्रोटो हिस्टरी आफ इंडिया' लिखी। वही द्वारिका प्रसाद मिश्र जब अगस्त के अंतिम सप्ताह में अचानक दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में प्रकट हुए, तो दूसरे ही दिन उनकी प्रधानमंत्री से भेंट हुई। नतीजतन राजधानी में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया।

'दादा' तो इससे इनकार करते हैं (वह कहते हैं एक्यूपंक्चर से इलाज कराने आये हैं) किंतु 'माया' को मिली जानकारी के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री निवास से निमंत्रण गया था। एक चर्चा यह भी थी कि अर्जुन सिंह उन्हें लाये थे। कारण और उद्देश्य कुछ भी हो, किंतु उनकी यात्रा संकटग्रस्त कांग्रेस के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। यह उन लोगों की सूची से ही स्पष्ट है जो उनसे मध्य प्रदेश भवन के कक्ष क्रमांक एक में मिल चुके हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं—अर्जुन सिंह, माखन लाल फोतेदार, बचपन के मित्र उमाशंकर दीक्षित, श्यामाचरण शुक्ल, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और सबसे महत्वपूर्ण किंतु रहस्यमय-आर०के० धवन। प्रस्तुत हैं, ८६ वर्षीय 'दादा' से 'माया' की बातचीत के अंश :

माया : राजीव गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में आपका क्या विचार है ?

मिश्र : राजीव गांधी के खिलाफ जो आंदोलन चला है, उसके बारे में मेरा कहना है कि अभी तक उनके खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

माया : प्रधानमंत्री के विरुद्ध लगे आरोप तो सिद्ध नहीं हुए, पर एक बात अवश्य सिद्ध हुई है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस एक-के बाद-एक जगह से हार रही है।

मिश्र : इसका उत्तर मेरे पास है। पहले तो पंजाब और असम को लीजिए। पंजाब से हरियाणा जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने स्वराज की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी। जनता को विश्वास हो गया कि हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। तब अंग्रेजों के सामने प्रश्न था कि हमारा आंदोलन चलने देते या हमसे समझौता करते। उन्होंने हमसे समझौता किया। जनता को विश्वास था कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं और उनकी भलाई करेंगे, इसलिए उसने हमें वोट दिया। इस प्रकार हम सत्ता में आ गये। पंजाब में अकालियों ने सिखों को विश्वास दिला दिया कि उनका जो आंदोलन है, वह उनके हित में है। असम में छात्रों का जो आंदोलन चला, उसमें भी लोगों को विश्वास हो गया कि छात्र उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। राजीव गांधी के सामने दो विकल्प थे—इन आंदोलनों को चलने देते अथवा समझौता करते। उन्होंने दूसरे को चुना और दोनों जगह समझौता किया। उन्होंने जिन लोगों से समझौता किया वे जीतकर आ गये। हरियाणा में इसलिए हार हुई कि पंजाब समझौते से वहां की जनता ने समझा कि हमारे हक मारे जा रहे हैं। इस तरह हरियाणा की हार राजीव-लोंगोवाल समझौते का परिणाम है। एक बात और, हरियाणा को जो हिंदी प्रदेश कहा जाता है, वह एक 'कर्टसी' है। यह क्षेत्र पहले पंजाब का एक भाग था। यह शताब्दी जब शुरू हुई, तो हिंदुओं ने कहना शुरू किया कि हमारी भाषा पंजाबी नहीं, हिंदी है। इसके पहले सब पंजाबी बोलते थे और ज्यादातर अखबार और लिखा-पढ़ी उर्दू में होती थी। न हिंदी में न पंजाबी में। एक बार जवाहर लाल नेहरू ने खुद मजाक में कहा था कि पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा का झगड़ा उर्दू भाषा के जरिए चलता है।

माया : बंगाल में कांग्रेस को अप्रत्याशित पराजय का मुंह क्यों देखना पड़ा ?

मिश्र : बंगाल में वे (शासक दल-माकपा) गहराई से जमे हैं। देहात में जो लगान प्रणाली थी, उसमें किसानों और सरकार के बीच बहुत से बिचौलिये थे। उन्होंने इन सबको मिटाकर देहात में अपनी स्थिति खूब मजबूत कर ली। वहां के कांग्रेसियों को यह समझना चाहिए था कि उनकी वहां चलेगी नहीं और वामपंथी मोर्चा जीतकर आयेगा। कांग्रेसियों को यह जानकारी राजीवजी को देनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं दी। फलस्वरूप उनकी (राजीव गांधी) इतनी बड़ी कोशिश भी कारगर साबित नहीं हुई। यदि इतनी बड़ी कोशिश न होती, तो लोग इसे इतनी बड़ी हार भी न बताते। इस प्रकार बंगाल में वे लोग जमे हुए हैं और उन्हें अभी हटाना बहुत मुश्किल है। वहां के कांग्रेस वालों पर ब्राह्मणों का यह मजाक लागू होता है—आठ कन्नौजिये नौ चूल्हे। वहां कांग्रेस बुरी तरह विभाजित है।

माया : राजीव गांधी के आने के बाद लगभग हर जगह यही स्थिति बन गयी है। कांग्रेस में आपसी संघर्ष बढ़ गये और एकता नहीं रही।

मिश्र : एक-एक बात को लेकर चलिए। बंगाल के बाद केरल को लें। वहां कांग्रेस के नेतृत्व में साझा सरकार थी। वहां की हार के दो कारण हैं। एक तो ई०एम०एस० नंबूदरीपाद, मार्क्सवादी पार्टी के सबसे चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उनके मुकाबले में केरल में अपना कोई नेता नहीं था। दूसरा मुस्लिम लीग जैसी जातीय पार्टी से समझौता करके हमने गलती की। जिस मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कराया, उससे समझौता मुझे कभी नहीं भाया।

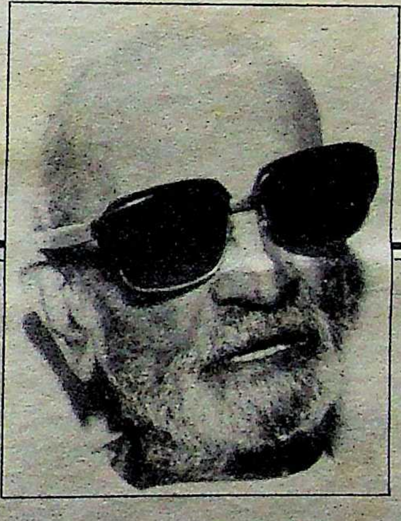

राजीव गांधी पुराने राजनीतिक तो नहीं हैं। वह राजनीति में नये-नये आये हैं। उन्हें अनुभव नहीं था कि लोग उनको अपने फायदे के लिए घेरेंगे। यह उनकी गलती है।

माया : लोग राजीव गांधी की इसलिए भी आलोचना करते हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों में जो फिरकापरस्त लोग और दल हैं, उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया।

मिश्र : केरल में यह गठबंधन तो इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है। राजीव गांधी ने उसको केवल चलने दिया। उनको चाहिए था कि वह खतम कर देते। यह उन्होंने नहीं किया।

माया : आपने कठिन समय में जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक रूप से मदद की थी। आपकी इस यात्रा से लोगों को लग रहा है कि आप राजीव गांधी की मर्दद करने आये हैं। उनको बचाने आये हैं।

मिश्र : देखिए मैं मान-न-मान मैं तेरा मेहमान नहीं बनना चाहता। इंदिराजी के समय में भी १९७१ के चुनाव के बाद उनकी सरकार में कुमारमंगलम का असर बढ़ा—बहुत से कम्युनिस्ट आ गये सरकार में और सोवियत संघ की ओर झुकाव बढ़ा। चन्द्रजीत यादव को पार्टी का सचिव बना दिया और बाद में वह इंदिराजी को छोड़ कर चले गये—उनकी मरजी के खिलाफ। मैंने इंदिराजी को एक चिट्ठी लिखी कि मैं गांधी युग का आदमी हूं। मैं कम्युनिस्टों की सलाह से थोड़े ही चल सकता हूं। मेरी यदि कोई उपयोगिता हो, तो मैं किसी की मदद करूं। यदि नहीं तो मैं जबरदस्ती क्या करूंगा ?

माया : क्या इससे यह निष्कर्ष निकाला जाये कि उन्होंने (राजीव गांधी) आपको मदद के लिए बुलाया और आप आये ?

मिश्र : नहीं मदद के लिए नहीं बुलाया। पर मैं उनसे मिला हूं। वैसे मैं अपनी औषधि के लिए एक हफ्ते यहां ठहरा हूं। यदि वह मुझे बुलायेंगे और ऐसा लगा कि मेरी मदद चाहिए, तो मैं दूंगा।

माया : अभी आपकी उनसे क्या बात हुई ?

मिश्र : यों ही औपचारिक। मेरे आने के बाद उन्हें (राजीव गांधी) फोन कर दिया गया था। वह दो दिन के दौरे पर बाहर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं यों ही पड़ा रहूंगा, इसलिए बुला लिया। दस मिनट तक मैं उनके साथ रहा। कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन उनकी बातचीत से मुझे लगा कि वह चाहते हैं कि फिर मिलें।

माया : जिस तरह के आरोप लगे हैं राजीव गांधी पर या उनसे जुड़े निकट के लोगों पर, उनसे एक शासक की जो विश्वसनीयता होती है, जो स्वतंत्रता के बाद से अब तक बनी रही है, वह खतरे में पड़ गयी है। आप क्या सोचते हैं ?

मिश्र : लेकिन क्या यह उनके कुसूर से हुई है, प्रश्न यह है। बिना सबूत के मात्र प्रचार करके क्या किसी को बदनाम किया जा सकता है ? यह अवश्य है कि विश्वसनीयता में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पर बिना किसी चीज के साबित हुए यह सब चल

रहा है। लोग कहते हैं कि राजीव गांधी इस्तीफा दे दें। एक बार जब सरकार चुनकर आती है, तो जब उसका कार्यकाल पूरा होता है, तब तो चुनाव कराना ही पड़ता है। लेकिन बीच में यदि मध्यावधि चुनाव होता है, तो जो पार्टी सत्ता में होती है, वह अपनी सुविधा देख कर, जब वह लोकप्रिय होती है तब चुनाव कराती है। श्रीमती थैचर ने जब दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कराया, तब वह फाकलैंड युद्ध जीतकर आयी थीं। उन्होंने ठीक समय चुना था। इस प्रकार जो पार्टी सत्ता में होती है, मध्यावधि चुनाव का समय चुनने का अधिकार उसका होता है, विपक्ष का नहीं। मान लीजिए ढाई साल जो सरकार के बचे हैं, उस बीच छवि फिर ठीक हो जाये।

माया : आपने कहा कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन धुआं तभी उठता है, जब आग होती है।

मिश्र : राजीव गांधी पुराने राजनीतिक तो नहीं हैं। वह राजनीति में नये-नये आये हैं। उन्हें अनुभव नहीं था कि लोग उनको अपने फायदे के लिए घेरेंगे। यह उनकी गलती है।

माया : उनकी इस गलती की देश को तो भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

मिश्र : देश को तो कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। अब ढाई साल वह क्या करते हैं, यह देखना है क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने अपने से दूर कर दिया है—ऐसा लगता है उनके आचरण से। इधर एक-दो महीने से मैं देख रहा हूं कि वह लोगों को हटा रहे हैं, पुराने लोगों से बात कर रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित ये सब पुराने लोग हैं। दीक्षितजी मुझ से उम्र में ७-८ महीने बड़े हैं और मैं उन्हें बड़ा भैया मानता हूं। कमलापतिजी से मैं साल-दो-साल बड़ा हूं। इन सब लोगों की राय-सलाह ले रहे हैं और भी बहुतों को लोगों ने आपसी झगड़े से निकाला। वे लोग नाराज हैं। संगठन में यह देखना चाहिए कि जो खराब लोग हैं, उन्हें निकालना चाहिए और जो लोग पार्टी की राजनीतिक उठा-पटक में निकाले गये हैं या चुपचाप घर बैठ गये हैं, उनको वापस लाना चाहिए।

माया : जिनको आप वापस लेने को कह रहे हैं क्या वे वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ आदि हैं?

मिश्र : अरे यह तो इनके (राजीव गांधी) समय में निकाले गये हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। हर प्रांत में मुख्यमंत्री अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो उनके प्रति वफादार होते हैं, उनकी राय-मदद लेते हैं और जिनका उनके साथ झगड़ा होता है, उनको अलग-थलग और कमजोर कर देते हैं। ऐसे लोगों में कुछ निराश होकर बैठ जाते हैं। इस प्रवृत्ति को ठीक करना चाहिए। बिहार का उदाहरण लें। मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे अपना ग्रुप बना रहे हैं और जगन्नाथ मिश्र अपना। मैं जब दिल्ली में था तो देखा करता था कि ललित नारायण मिश्र एक के बाद एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर चार-छह महीने रहने देते, फिर उसको निकाल दिया करते थे—यदि जरा भी उनकी मरजी के खिलाफ वह काम करता। जवाहर लालजी के समय में एक अच्छी परंपरा थी कि कांग्रेस पार्टी को अपना नेता चुनने का हक मिलता था। इंदिराजी ने इसको गड़बड़ कर दिया। दुबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तखतमलजी से मुझे कंटेस्ट करना पड़ा। जब मैं मुख्यमंत्री हुआ था, तो सिर्फ एक आदमी यह देखने के लिए दिल्ली से गया था कि वोट ईमानदारी से पड़ा या नहीं। पार्टी किसी को आरोपित नहीं करती थी।

एक साधारण
कांग्रेस कार्यकर्ता जो
थोड़े समय में ही शीर्ष
पर पहुंचता है, उसको
राजनीतिक अनुभव आखिर
कितना होगा?

माया : क्या यह विचित्र नहीं कि पार्टी में १९७२ से चुनाव नहीं हुए?

मिश्र : यह बिलकुल गड़बड़ है। चुनाव होना चाहिए।

माया : राजीव गांधी बदल तो अवश्य रहे हैं, पर आगे उनकी क्या दृष्टि होगी, देश, पार्टी और सरकार की क्या दिशा होगी, यह स्पष्ट नहीं है।

मिश्र : जो संसद सदस्य होते हैं, उन्हीं में से तो सरकार बनायी जाती है। जो लोग चुनकर आये हैं, उनमें टेलेंट बहुत कम हैं।

माया : इसका जिम्मेदार तो वही हुआ, जिसने टिकट बांटे हैं।

मिश्र : कुछ नये लोग लिये गये हैं। मेरा अनुभव है कि पुराने कांग्रेसी जो थे उनको तो इन्होंने आते ही खराब बता दिया—सत्ता के दलाल आदि कहकर। बाद में एक नयी युवा कांग्रेस बनी। मेरा अनुभव है कि म०प्र० में जो नये लड़के आये हैं, उनमें कुछ तो अच्छे हैं बाकी सब खराब हैं। वे अपना कैरियर बनाने आये हैं। हम पुराने लोगों की तरह नहीं कि भाई स्वराज नहीं मिलेगा, तो सारी जिंदगी लड़ेंगे। वह भावना तो अब रही नहीं।

माया : आपने अपनी राजनीतिक सक्रियता के दिनों में राजाओं-सामंतों से टक्कर ली थी। अब यह मान्यता है कि कांग्रेस में उन्हीं राजाओं-सामंतों का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे कई विकृतियां पैदा हो रही हैं। संसद, सरकार में राजा-महाराजा बढ़ गये हैं। जिससे लोगों को चिंता हो गयी है कि कांग्रेस किस ओर जा रही है।

मिश्र : लोगों की यह चिंता वाजिब है। यह बहुत गलत काम हुआ था। मैंने एक बार यह कहा था, तो ग्वालियर की महारानी बहुत नाराज हो गयी थीं। मैंने तब कहा था कि जो राजा-महाराजा आ गये हैं, वे श्रमिकों की तरह यूनियन बना रहे हैं, अपनी एकता कर रहे हैं। यह बहुत खराब बात है। जिनको हमने खतम किया उनको नयी जिंदगी दी जा रही है।

माया : यह भी तो कांग्रेस ही कर रही है।

मिश्र : यह तो चला आ रहा है इंदिराजी के समय से। इन्होंने (राजीव गांधी) कुछ नया नहीं किया। आप यह देखें कि कितनी समस्याएं इन्हे विरासत में मिलीं और कितनी स्वयं पैदा कीं। जो खुद पैदा की हैं, उनके लिए तो उन्हें दोष दें जो विरासत मे मिली हैं, उनके बारे में यही कहें कि चली आ रही है।

माया : उन्होंने (राजीव गांधी) पुरानी समस्याएं दूर कहां कीं?

मिश्र : उन्होंने इधर-उधर के परिवर्तन करने की बात की। यह नहीं देखा कि इंदिराजी के समय से जो खरात तत्व हैं, उन्हें टिकट न दिया जाये। जैसा मैंने कहा कि एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता जो थोड़े समय में ही शीर्ष पर पहुंचता है, उसको राजनीतिक अनुभव आखिर कितना होगा? इसी कारण कई गलतियां हुईं। थोड़ा सीख जायेंगे तो ठीक हो जायेगा।

माया : क्या आपको विश्वास है कि राजीव सीख जायेंगे?

मिश्र : मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए चार छह माह ठहर कर देखना होगा।

—राहुल देव

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

धौ.

एक मस्तूली जहाज जिसे प्राचीन भारत में बनाया जाता था. जहाज निर्माण भारतीय उद्योग में प्रमुख स्थान रखती थी और उन दिनों भारतीय जहाज विश्व के कई देशों में निर्यात किए जाते थे. इसलिए धौ भारतीय कला-कौशल और हुनर का प्रतीक है जिसने सबको बेहतर जीवन जीने की राह दिखाई.

समृद्धि की लहर

भारत के सदियों से चले आ रहे विश्व व्यापार के विकास में हम अपने स्वप्नों का प्रतिबिंब देखते हैं. एक ऐसा स्वप्न जो राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सशक्त बनाने में हमारी कटिबद्धता का मूल आधार है.

चाहे प्रोसेस्ड फूड्स हों या इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़े हो या कालीन, चमडा या चमड़े की वस्तुएं, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि राष्ट्रीय राजस्व विभाग को इन उत्पादनों को उच्चतम अंतरराष्ट्रीय कीमत मिले.

इसके साथ ही, हम लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को प्रबंधकीय और तकनीकी निवेश की सहायता के ज़रिए उन्हें उत्तमता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

हालांकि यह हमारी (रैलीज़ इन्डिया) सफलता है कि विदेशों में हमारे उत्पादनों की माँग बढ़ रही है.

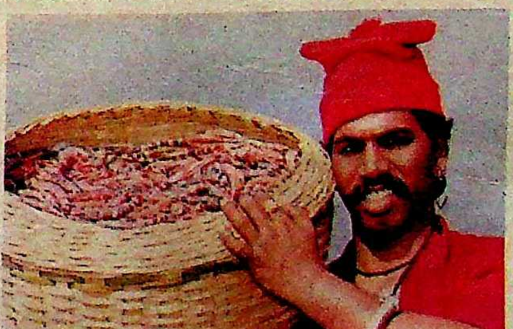

किंतु हमारा अपना आत्म-संतोष कहीं और ही है : यह इस जानकारी में है कि भारत के निर्यात में १० गुना वृद्धि हुई है, १९६६-६७ में रु. १,१५७ करोड़ से १९८५-८६ में रु. ११,०१२ करोड़ और राष्ट्र के विदेशी मुद्रा कोष में २५ गुना वृद्धि हुई है, रु. २९६ करोड से इसी दौरान रु. ७,३८४ करोड.

हर चढते सूरज के साथ जैसे-जैसे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मज़बूत होती जा रही है, जीवन स्तर भी बेहतर होता जा रहा है. भविष्य उज्ज्वल है.

वास्तव में, वो समृद्धि जो हम अपने स्वप्नों में देखते हैं, साकार हो उठती है राष्ट्र की विकासशील सशक्त अर्थव्यवस्था में.

बेहतर है जीवन, रैलीज़ के संग

RALLIS
Multi-Technology Group

Agrochemicals
Consumer Durables
Control Systems
Engineering
Pharmaceuticals
Exports

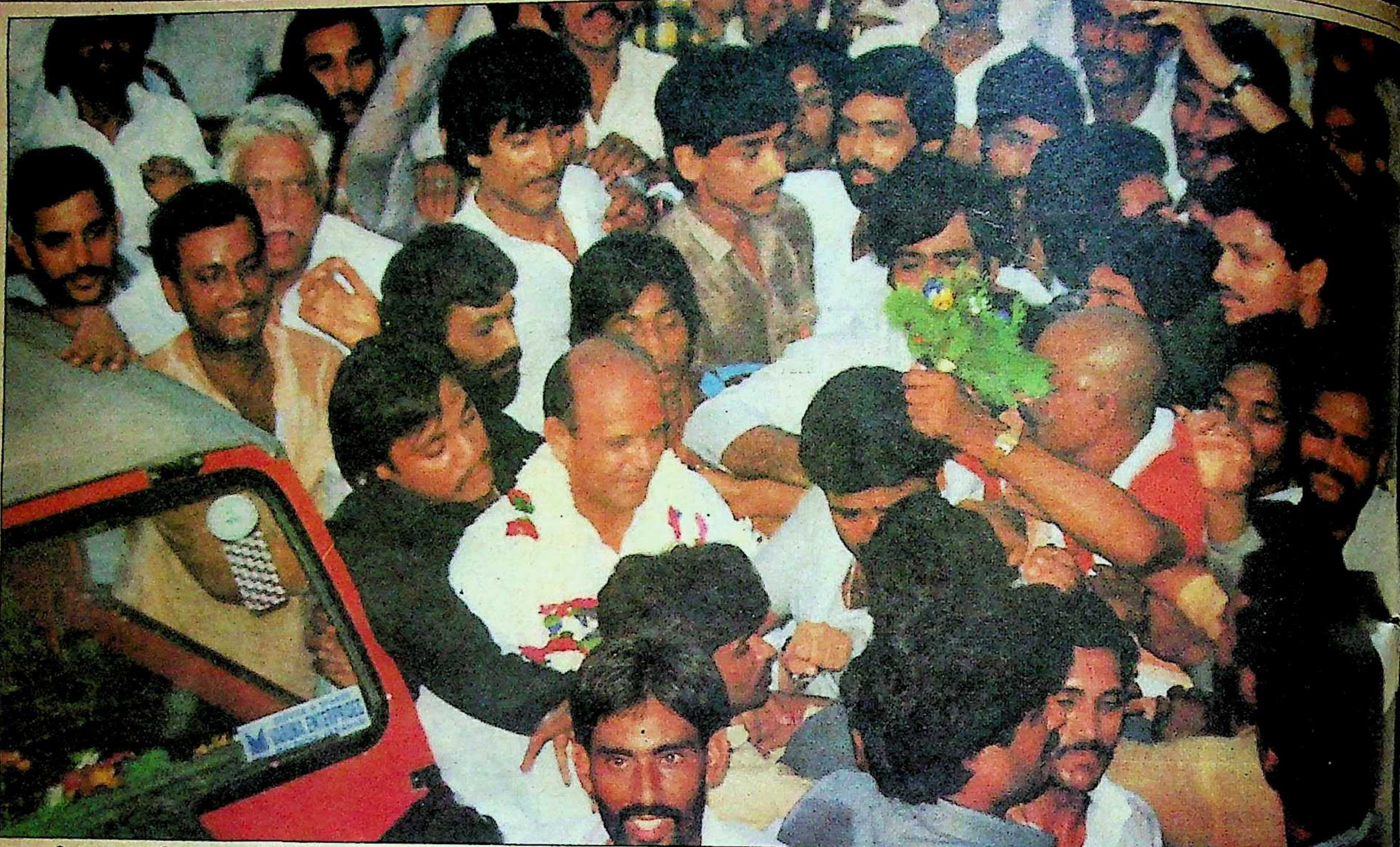

अप्रत्याशित जन समर्थन

छाया : विजय सिंह

बनारस में वी०पी० सिंह

कांग्रेस के किले में सेंध

३० अगस्त को वी०पी० सिंह के बनारस-दौरे ने काफी खलबली मचायी है। यहां न केवल उन्होंने संख्या के लिहाज से ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया, बल्कि उन्होंने 'राजर्षि' की दुर्लभ उपाधि भी प्राप्त की। वी०पी० सिंह के इस दौरे से इंका के अपेक्षाकृत अधिक परेशान होने का कारण क्या है? 'राजर्षि' की उपाधि विवाद का मुद्दा क्यों बनी है?

यों तो बनारस रांड, सांड और संन्यासियों के लिए मशहूर है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्नायु केंद्र है। इतना ही नहीं, यहां के धमाके की अनुगूंज मध्य प्रदेश और बिहार के समीपस्थ क्षेत्रों तक पहुंचती है। जातीय राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण-राजनीति के मौसम की जानकारी के लिए बनारस 'इनसेट-एक बी' जैसी भूमिका निभाता है। इस ब्राह्मण-राजनीति के मठाधीश पंडित कमलापति त्रिपाठी हैं—यह पहले हकीकत थी, लेकिन अब यह मात्र मुगालता है।

३० अगस्त को वी०पी० सिंह करीब ४०० कारों के काफिले के साथ, बेनियाबाग मैदान में लगभग एक लाख लोगों की भीड़ को संबोधित करके शायद इसी मुगालते को तोड़ने और कांग्रेस के किले—पूर्वी उत्तर प्रदेश—में सेंध लगाने पहुंचे थे।

कोशिशें नाकाम : ऐसी संवेदनशील जगह पर वी०पी० सिंह जैसा 'आततायी' पहुंचे और इंका आलाकमान हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहे—यह कैसे हो सकता था। यहां के राजनीतिक मोर्चे के बूढ़े समर-विशेषज्ञ पंडित कमलापति त्रिपाठी, मुख्य-मंत्री-पद के चिरंतन दावेदार अपने पुत्र के साथ आकर जम गये। यों पंडितजी का २६ अगस्त को ८३वां जन्म दिन था। इस अवसर पर होनेवाले समारोह में शामिल होने के लिए वह यहां पहुंचे थे। लेकिन शायद यह पहला मौका था, जब पंडितजी ऐन दिन पर पहुंचने के बजाय काफी पहले यहां आ

पूर्वी उ०प्र० को प्रभावित करने का अभियान : जीप पर अरुण नेहरू, वी०सी० शुक्ला, संजय सिंह, मुफ्ती, सुरेंद्र सिंह

छाया : विजय सिंह

विरोध करने का इंकाई तरीका : वी०पी० सिंह का पुतला जलाने के बाद मार्ग को अवरुद्ध किये इंकाई

छाया : विजय सिंह

पहुंचे। उधर मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह अचानक बनारस पहुंचे। उन्होंने माहौल सूंघा, 'इंतजाम' देखा और फिर पूजा-पाठ करके लखनऊ लौट गये। केंद्रीय और प्रादेशिक गुप्तचर संगठन सक्रिय थे ही—जनता के मूड और कौन किससे मिल रहा है, का पता लगाने के लिए। मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं और विधायक बागी न हो जायें। यह चिंता भू०पू० सांसद चंद्रशेखर सिंह के इस दावे से जनमी थी कि इंका के पांच हजार कार्यकर्ताओं ने वी०पी० सिंह के प्रति आस्था व्यक्त की है और ४० विधायक जनसभा में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने संभावित बगावत पर अर्गला लगाने के लिए पांच विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, ताकि बाकी लोग भयभीत हो सकें। ये विधायक हैं—जयदीप सिंह बरार, मुहम्मद असलम खां, अरुण प्रताप सिंह, उदयवीर सिंह तथा कैप्टन बलदेव सिंह।

ऐसी अफवाह थी कि इस जनसभा में नये बागी विधायकों को पेश किया जायेगा, लेकिन न ऐसा हुआ और न ही ऐसी कोई गंभीर योजना थी, क्योंकि अब वी०पी० सिंह की एक साथ धमाका करने की योजना है। यानी जब तक सरकार गिराने लायक संख्या नहीं हो जाये, तब तक वह अपने समर्थकों को पार्टी से चिपके रहने की सलाह दे रहे हैं।

विशाल जनसभा : जहां तक वी०पी० सिंह की जनसभा के आकार का सवाल है, इसे तीसरी सबसे बड़ी जनसभा माना जा रहा है। इससे पहले इतनी विशाल सभा को जयप्रकाश नारायण ने

भरोसे के दो मशहूर नाम.

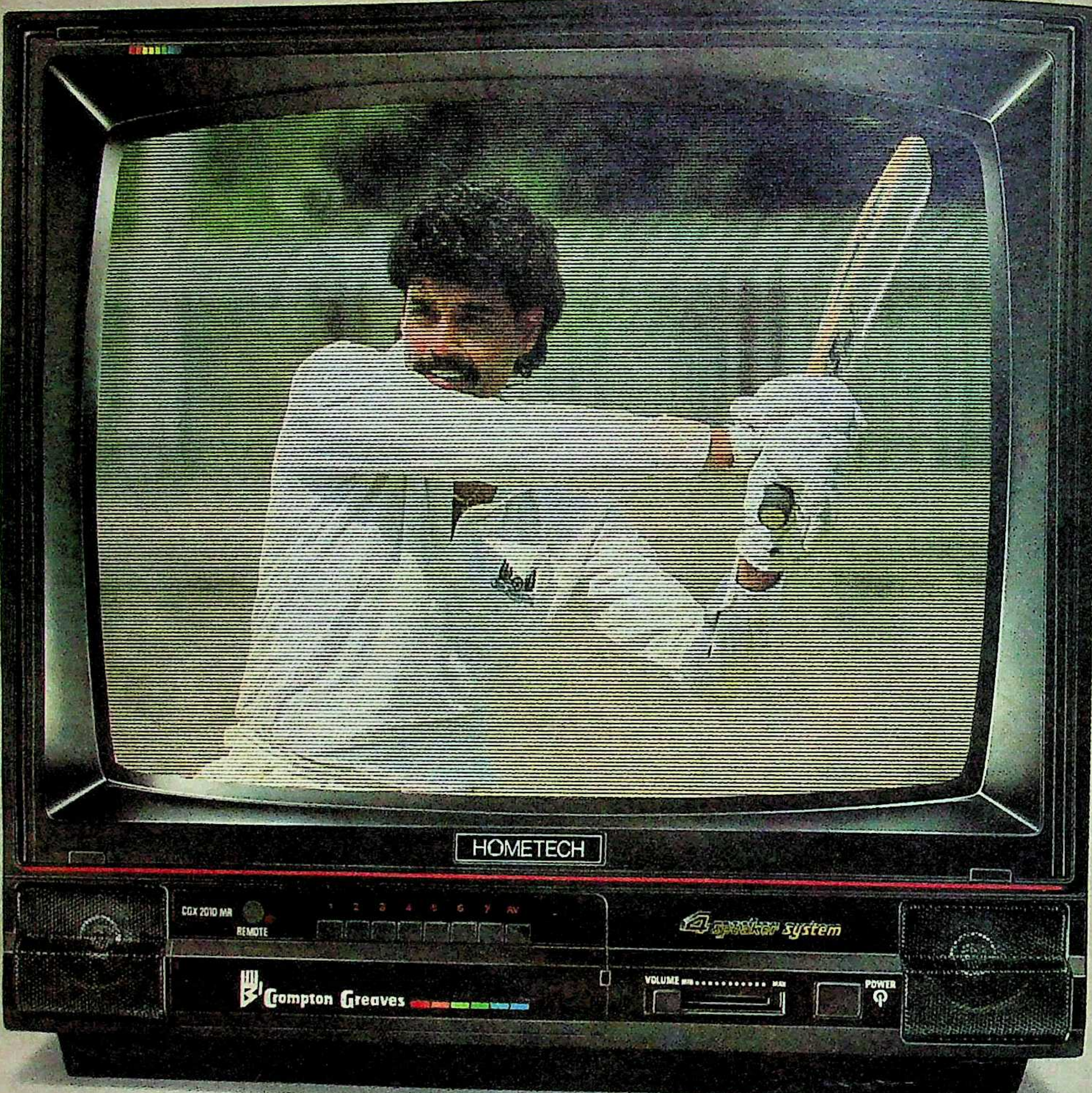
HOMETECH
CGX 2010 MR
REMOTE
1 2 3 4 5 6 7 AV
4 speaker system
Crompton Greaves
VOLUME
POWER

क्रिकेट-स्टार दिलीप वेंगसरकर ने आज तक आपको कभी निराश नहीं किया. और इस सीज़न में भी आप उनसे कमाल के करिश्मों की उम्मीद कर सकते हैं. उनके सहज भरोसे के खेल ने ही उन्हें विस्डन के विश्व के पांच 'क्रिकेटर्स ऑफ़ द इयर' में स्थान दिलाया. यही नहीं, डेलॉइट्स के कम्प्यूटर ने भी उन्हें दुनिया के पहले नंबर के बल्लेबाज का खिताब दिया. वैसे यहां हम आपको एक दूसरे मशहूर स्टार के बारे में बतायेंगे. क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कलर टेलीविजन. एक ऐसा टेलीविजन जो बना है आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से. कितनी ही अन्य खूबियां है इसमें जो इसे एक खास टीवी बनाती हैं.

और सबसे बड़ी बात यह कि क्रॉम्प्टन ग्रीव्स टीवी देता है आपको १२ महीने का व्यापक बीमा जिसमें आपके टीवी का सबसे क़ीमती पुर्ज़ा पिक्चर ट्यूब भी शामिल होता है. बिक्री के बाद 'सर्विस' की ऐसी बेजोड़ सुविधाएं भी, जो शायद ही कहीं और मिलें. दरअसल, यह टीवी क्रॉम्प्टन ग्रीव्स ने बनाया है.

और स्वाभाविक है कि बरसों से अर्जित अपनी शान को क़ायम रखने के लिए क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

Crompton Greaves
LIMITED

क्रॉम्प्टन ग्रीव्स टीवी.
क्योंकि कुछ चीज़ें देती हैं मज़ा बरसोंबरस.

कन्ज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउसहोल्ड एप्लाएन्सेज़ डिवीज़न, पैविले हाउस, बॉम्बे डाइंग कम्पाउन्ड, प्रभादेवी, बम्बई ४०० ०२५. फोन - ४३० ०९५१, ४३० ०९५२.

Enterprise/CGL/H

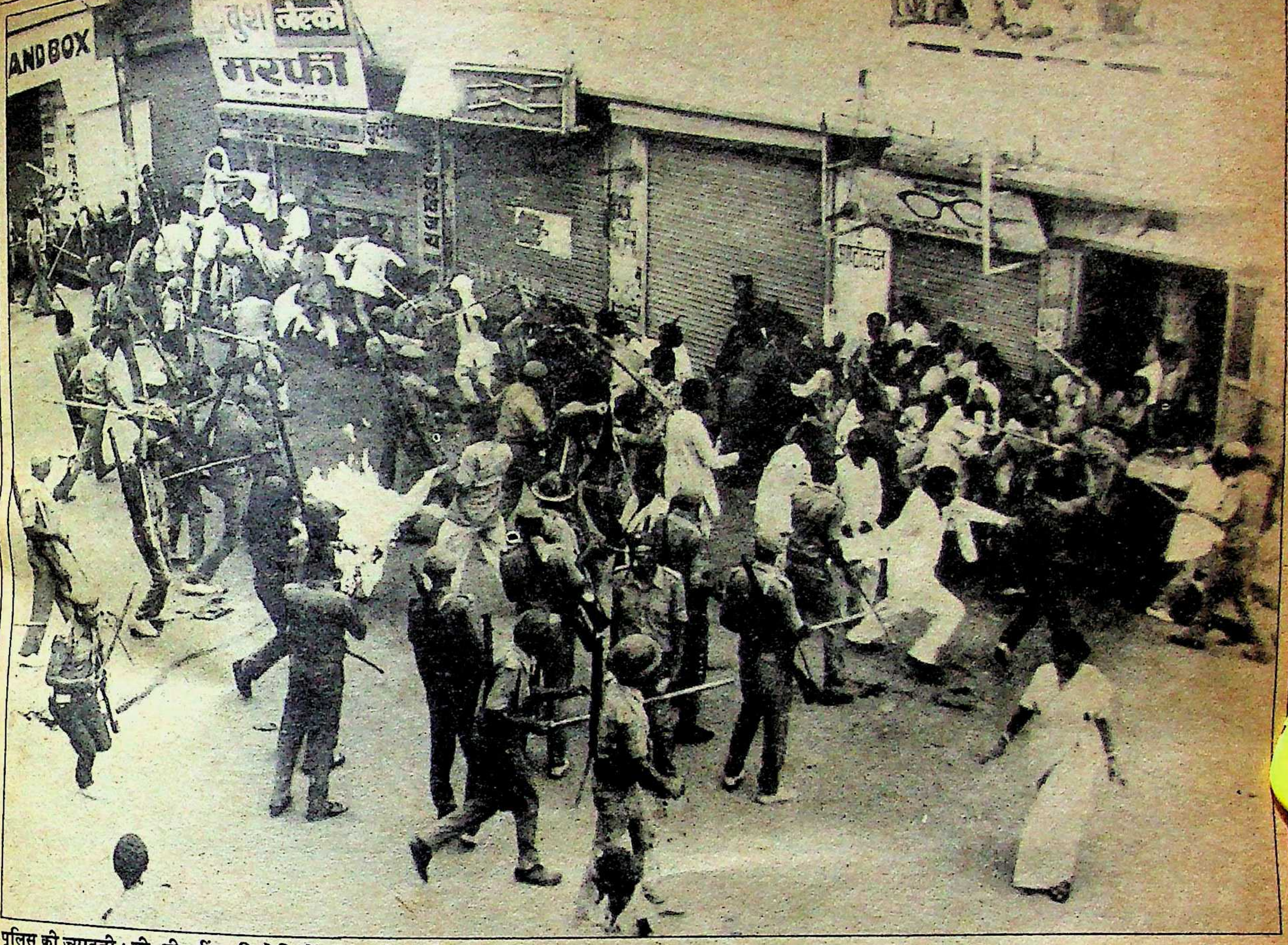

पुलिस की ज्यादती : वी०पी० सिंह विरोधियों पर लाठी चार्ज

छाया : क्लाउन

१९७४ में संबोधित किया था। दूसरी १९७६ में संजय गांधी की जनसभा थी, जिसमें काफी लोगों को घेर कर लाया गया था, लेकिन इस बार वी० पी० सिंह के प्रति जोश का आलम यह था कि बाबतपुर हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक १८ किलोमीटर का रास्ता तय करने में वी०पी० सिंह के ४०० कारों के काफिले को तीन घंटे लगे। रास्ते में २५ स्थानों पर उनका अभिनंदन हुआ। वी०पी० सिंह के साथ अरुण नेहरू, रामधन, आरिफ मोहम्मद खान आदि तो थे ही। अभी कांग्रेस में बरकरार मुफ्ती मोहम्मद सईद भी साथ थे। इसके अतिरिक्त बड़ौदा के मेयर, गुजरात के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक जसपाल सिंह भी थे।

इस जनसभा की तैयारी के लिए संजय सिंह तो पहले से लगे ही थे। इसके अतिरिक्त, वी०पी० सिंह के पहले बनारस में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, लोकदल-अ के अध्यक्ष अजीत सिंह व सत्यप्रकाश मालवीय, हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, आरिफ मोहम्मद खान ने जनसभाओं को संबोधित करके माहौल काफी गरम कर दिया था। यद्यपि जनसभा में जनता पार्टी ने अतिरिक्त उत्साह दिखाया, लेकिन मोटर साइकिलों के काफिले में सभी पार्टियों के झंडे दिखायी पड़ रहे थे।

पत्रकार स
प्रेस से मिलिए
कार्यक्रम
AGARWAL

मुझे सत्ता नहीं चाहिए : वी०पी० सिंह

छाया : क्लाउन

चूंकि वी०पी० सिंह की जनसभा में आरिफ मोहम्मद खान, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जफर अली नकवी उपस्थित हो रहे थे, इसलिए शहर के मुस्लिम समुदाय का भरपूर समर्थन मिलने की संभावना थी। इसलिए वी०पी० सिंह के आगमन से कुछ दिन पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में 'मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट आफ इंडिया' नामक संगठन की ओर से रातोंरात उर्दू में लिखे परचे बांटे गये। जिनमें मुरादाबाद में १९८० में हुए दंगों का जिक्र करके वी०पी० सिंह को मुस्लिम-विरोधी करार दिया गया था। उस समय वी०पी० सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस परचे में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए भी वी०पी० सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इंका के भूतपूर्व सांसद रामेश्वर सिंह और लोकदल-ब के नेता नन्हे खां ने इन परचों के पीछे इंका के लोगों का हाथ माना है।

रस्मी विरोध : इन परचों का तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इंका के नौजवानों ने पुलिस को लाठी चार्ज करने के लिए अवश्य बाध्य कर दिया।

'राजर्षि' विश्वनाथ प्रताप सिंह

'काशी विद्वत परिषद' चार सौ साल पुरानी संस्था है, जिससे चारों शंकराचार्य जुड़े हैं। इस संस्था पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। यह संस्था किसी को सम्मानित करती है, तो वह व्यक्ति ब्राह्मणों में सम्मानित माना जाता है। वी०पी० सिंह को इसी संस्था ने 'राजर्षि' की उपाधि प्रदान की है, जिसको लेकर अब 'युद्ध' छिड़ा हुआ है। वी०पी० सिंह को यह उपाधि मिलने पर अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह मात्र ठाकुरों के समर्थन पर टिके हैं। यह सीधे-सीधे कमलापति त्रिपाठी के एकाधिकार को चुनौती है।

उपाधि प्रदान करने के अवसर पर काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो० वीरभद्र मिश्र, अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पंडित सूर्य नारायण मिश्र, सार्वभौम ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पंडित मदुनंदन उपाध्याय, सरयूपारी ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मैथिल ब्राह्मण परिषद के हीरानंद झा और २०० से अधिक विद्वान एक विशेष मंच पर उपस्थित थे। अखिल भारतीय श्री पंडित परिषद के मंत्री इंदू शेखर पाण्डेय ने वी० पी० सिंह को 'राजर्षि' की उपाधि दिये जाने की घोषणा की। 'काशी विद्वत परिषद' के वयोवृद्ध पंडित नौरंग चतुर्वेदी ने श्री सिंह को अभिनंदन पत्र भेंट किया। संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान के संचालक बागीश शास्त्री ने श्री सिंह का स्वागत किया। 'विद्वत् परिषद' के मंडप में भी सिंह के साथ विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री संजय सिंह, सुरेंद्र सिंह और सांसद राजकुमार राय भी मंच पर विराजमान थे।

श्री सिंह ने सभी विद्वानों और पंडितों को माला पहनाकर और चंदन लगाकर पूजन किया। उन्होंने 'काशी विद्वत परिषद' के अध्यक्ष शिव कुमार शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। श्री सिंह राजेंद्र प्रसाद के बाद पहले राजनेता हैं, जिन्हें काशी के विद्वानों की पूजा करने का अवसर मिला। यह समारोह सामान्य राजनीतिक समारोह से एकदम भिन्न था, लेकिन देश में चरित्र के संकट की चर्चाओं के जरिये विद्वानों ने भ्रष्टाचार और दलाली के खिलाफ वी०पी० सिंह के अभियान को अपना समर्थन दिया।

पंडित कमलापति त्रिपाठी बनारस में हों और वी०पीं० सिंह को ब्राह्मणों द्वारा 'राजर्षि' की उपाधि दी जाये—भला इससे बढ़कर 'पाप' क्या हो सकता था! नतीजतन उपाधि विवादों से घिर गयी। सूत्रों का कहना है कि जब पंडितजी दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली दरबार ताव खाये बैठा था कि उनकी उपस्थिति में बनारस के ब्राह्मणों ने वी०पी० सिंह का सम्मान कैसे कर दिया। पंडितजी एक खेल हार चुके थे। वह क्या कहते, पर उन्होंने दिल्ली दरबार को आश्वस्त किया कि यह उपाधि असली नहीं है, वह इसे साबित कर देंगे। बस इसी के बाद पंडितजी ने दिल्ली में बैठकर बनारस के अपने लोगों को खटखटाया और उपाधि को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

विवाद के प्रथम चरण में कहा गया कि 'काशी विद्वत परिषद' जिसने वी०पी० सिंह को 'राजर्षि' की उपाधि प्रदान की, का वी० पी० सिंह समर्थकों द्वारा अपहरण किया गया है। वी०पी० सिंह-समर्थकों ने काशी विद्वत परिषद के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला कर यह उपाधि इसलिए हासिल की कि इससे भ्रम फैलेगा कि पूरा ब्राह्मण वर्ग राजा साहब का समर्थन कर रहा है। यह भी कहा गया कि परिषद के चार शंकराचार्य जो इसके प्रमुख स्तंभ हैं, ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। श्री सिंह को उपाधि का दिया जाना एक प्रकार से परिषद पर अवैध कब्जा था।

श्री काशीविद्वत्परिषद वाराणसी

ब्राह्मण समर्थन : 'राजर्षि' सम्मान के समय मंच पर वी०पी० सिंह

छाया : विजय सिंह

परिषद के एक वर्ग का कहना है कि जिन अनधिकृत व्यक्तियों ने परिषद के वास्तविक कार्यालय संचालकों के विरोध और मना करने के बावजूद परिषद के नाम पर कार्य किया, उनमें सुरेंद्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अंबिका सिंह, इंदूशेखर पाण्डेय और वीरभद्र मिश्र शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए धन दिया।

परिषद के अध्यक्ष ६० वर्षीय एन० पति मिश्र इस समय गंभीर रूप से बीमार हैं। परिषद के उपाध्यक्ष राधेश्याम मिश्र और महासचिव पतिराम शास्त्री ने अखबारों में और सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने इस आयोजन में भाग नहीं लिया। कार्यालय संचालकों की बिना अनुमति लिये उनके नाम आमंत्रण कार्ड पर छापे गये। परिषद के दो कार्यालय संचालकों ने वी०पी० सिंह को दिल्ली तार भेजकर सूचित किया है कि 'काशी विद्वत परिषद' उनका विरोध करता है।

परिषद के कोषाध्यक्ष श्याममूर्ति उपाध्याय ने पं० कमलापति त्रिपाठी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि अखिलानंद शर्मा को महासचिव के रूप में दिखाया गया है, जबकि वास्तव में वह इस पद पर कभी नहीं रहे।

पं० कमलापति त्रिपाठी इस विचार से

सहमत हैं कि वी०पी० सिंह को दी गयी उपाधि व्यर्थ है, क्योंकि इसको परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। श्री त्रिपाठी का मानना है कि जब परिषद के महासचिव ने इस बात को साबित कर दिया है कि समारोह अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया था, तो जो उपाधि वी०पी० सिंह को मिली है, वह 'काशी विद्वत परिषद' द्वारा नहीं दी गयी है। उपाधि को लेकर विवाद सिर उठा रहे हैं, पर पूछनेवाले सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक भव्य समारोह में वी०पी० सिंह को 'राजर्षि' की उपाधि दी जा रही थी, तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया? दिल्ली पहुंचने के बाद ही पंडितजी को क्यों लगा कि उपाधि देने में साजिश हुई है? वैसे सी०पी०एम० के नेता बी०टी० रणदिवे ने भी इस उपाधि को स्वीकार करने के लिए वी०पी० सिंह की आलोचना की है, लेकिन उनकी आलोचना का आधार सैद्धांतिक है। उनका कहना है कि यह उपाधि प्राप्त करके वी०पी० सिंह प्रतिक्रियावादी शक्तियों के चंगुल में फंसे हैं।

—दिनेश दीनू

छाया : क्लाउन

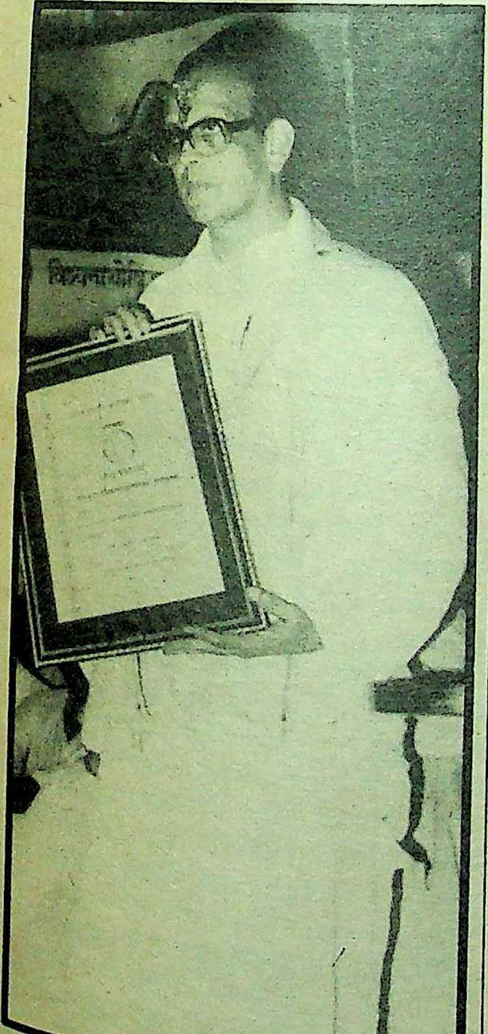

दुर्लभ सम्मान : उपाधि-पत्र के साथ वी०पी० सिंह

इंकाई नौजवानों ने पहले वी०पी० सिंह का पुतला जलाया और फिर पुतले के जलते हुए टुकड़ों को वी०पी० सिंह के सम्मानार्थ सड़क के आस-पास खड़ी भीड़ पर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन पिटे हुए इंकाइयों को ढाढ़स देने के लिए एक सितंबर को प्रदेश के गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित बनारस पहुंचे। बाद में इन इंकाइयों ने लखनऊ पहुंच कर कांग्रेस दफ्तर में शिकायत की और वहां टंगी वी०पी० सिंह की तस्वीर को उतार कर पैरों से कुचल कर अपना गुस्सा मिटाया। उस समय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी वहां मौजूद थे। अब ये इंकाई मांग कर रहे हैं कि 'दोषी' पुलिस अधिकारी दंडित हों।

लेकिन वी० पी० सिंह पर अब ऐसे रस्मी विरोध का कोई असर नहीं होता। इसलिए जनसभा के अतिरिक्त उन्होंने दूसरे दिन ३१ अगस्त को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में छात्रों को तथा कचहरी में वकीलों को संबोधित किया।

सबसे बड़ी उपलब्धि : लेकिन वी०पी० सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि 'राजर्षि' की उपाधि पाना है। यह उपाधि १९५२ में हिंदी के अनन्य पक्षधर पुरुषोत्तम दास टंडन को दी गयी थी। इसके बाद इस उपाधि को पाने वाले वी०पी० सिंह पहले व्यक्ति हैं। वी०पी० सिंह पर कमलापति त्रिपाठी यह आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ

बनारसी नारे

तख्त बदल दो ताज बदल दो बेइमान
बदल दो
निवेदक

छाया : विजय सिंह

बनारस, प्रसाद एवं धूमिल जैसे महान और चकाचक बनारसी जैसे 'अतिमहान' कवियों की भूमि है, इसलिए यह कैसे हो सकता है कि राजनीतिक नारों के प्रणेताओं की कमी हो। वी०पी० सिंह को इसीलिए यहां जोरदार नारों का तोहफा मिला। नमूने के लिए कुछ नारे यहां प्रस्तुत हैं :

१. राजा नहीं फकीर है, मजलूमों का पीर है।
२. विश्वनाथ की नगरी में, विश्वनाथ का स्वागत है।
३. वी०पी० का जोर है, राजीव गांधी चोर है।
४. जनता पूछती है एक सवाल, बोफोर्स का कौन दलाल?
५. राजा का यह फरमान, नहीं बिकेगा हिंदुस्तान।
६. राजा का क्या आदेश, देशद्रोहियों छोड़ो देश।
७. राजा की हो क्या अभिलाषा, रहे न कोई भूखा प्यासा।
८. तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेइमानों का राज बदल दो।

यों तो राजा ने अपने भाषण में वही भ्रष्टाचार उन्मूलन का पुराना राग अलापा, लेकिन कुछ लोकलुभावनकारी बातें भी कहीं। उन्होंने बच्चों को 'एबीसी' पढ़ाने के लिए नया गुर सिखाया। उन्होंने कहा 'ए' फार अमिताभ, 'बी' फार बोफोर्स, 'सी' फार चड्ढा। बाद में 'डी' याद कराने के लिए 'बहूजी' (पंडित कमलापति त्रिपाठी की पुत्रवधू और उ०प्र० के स्वास्थ्य मंत्री की धर्मपत्नी चंद्रा त्रिपाठी) ने कहा 'डी' फार डहिया (उनका मतलब विवादास्पद डहिया ट्रस्ट से था)। बहूजी ने 'राजर्षि' उपाधि मिलने का भी मखौल उड़ाया है। उनका कहना है, 'राजर्षि' की उपाधि विद्वानों को मिलती है, जबकि वी०पी० सिंह में कोई विद्वत्ता नहीं—तुकबंदी कर लेने से कोई कवियों की श्रेणी में नहीं आ जाता।

—दिनेश दीनू

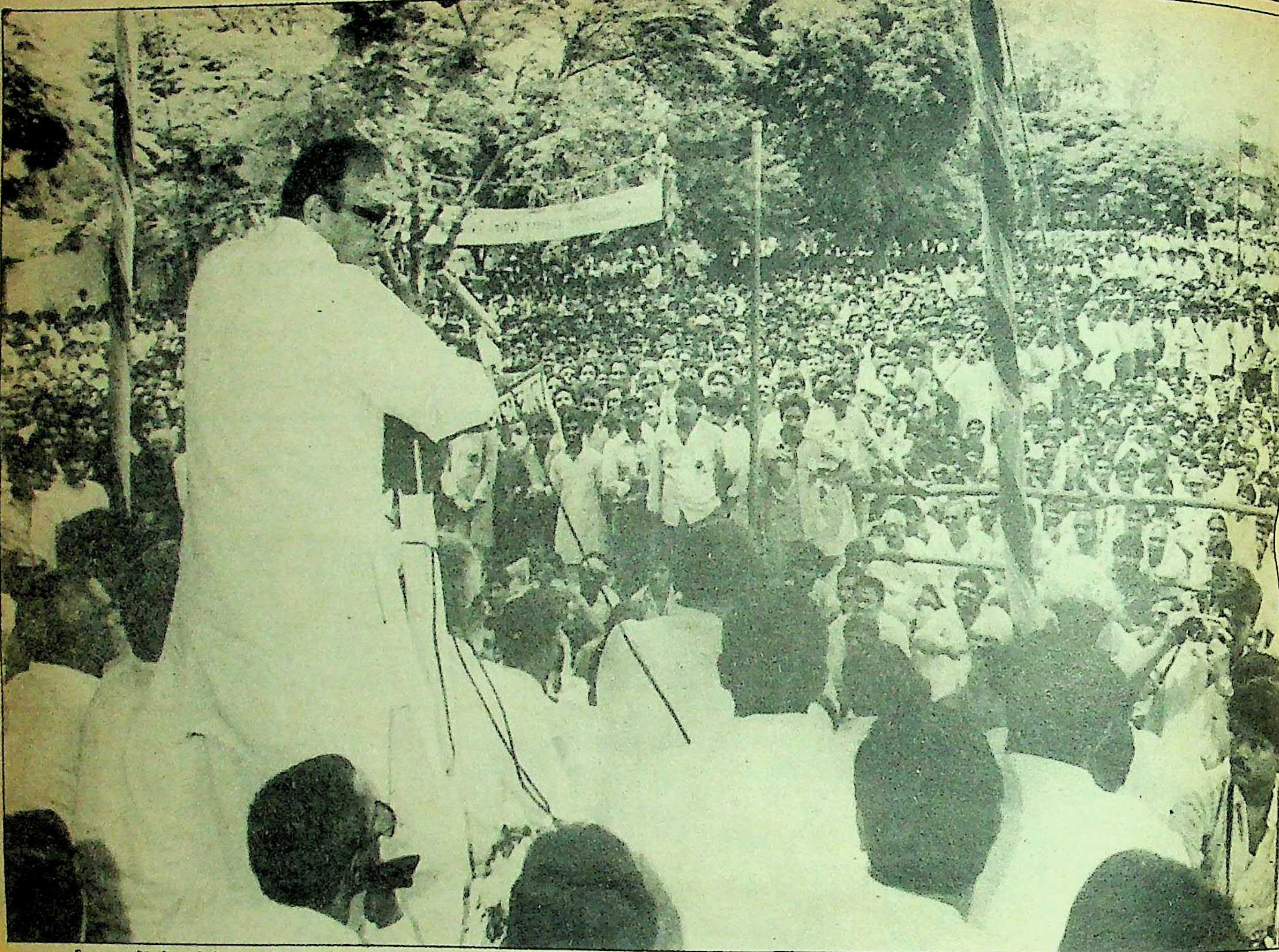

युवा समर्थन : छात्रों को संबोधित करते हुए वी०पी० सिंह

छाया : क्लाउन

केवल भूतपूर्व राजा-रजवाड़ों के लोग हैं या ठाकुर। इस उपाधि को प्राप्त करने के पीछे कमलापति त्रिपाठी के इसी आरोप का जवाब देना था। क्योंकि जो संस्था—काशी विद्वत परिषद—यह उपाधि देती है, वह ब्राह्मणों में काफी सम्मानित संस्था है। अब इस उपाधि को अवैध करार देने की मुहिम शुरू हो गयी है (देखिए बाक्स)।

तीन तेरह : उपाधि और बनारस में राजा मांडा को अभूतपूर्व समर्थन मिलने से इंका का चितित होना स्वाभाविक है। लेकिन, यह चिता बनारस में सक्रिय तीन इंका नेताओं द्वारा दूर होती नजर नहीं आती, क्योंकि ये तीनों गुट एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं। इन तीन गुटों के नेता हैं—पं० कमलापति त्रिपाठी, श्याम लाल यादव और रत्नाकर पाण्डेय। श्यामलाल यादव राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। अब वह मात्र सांसद हैं। श्यामलाल यादव और उनके राजनीति में जमने के आकांक्षी पुत्र अशोक यादव अपनी अलग खिचड़ी पकाते हैं और राज्यसभा के सदस्य रत्नाकर पांडेय दिल्ली में बैठ कर अपने भाई सुधाकर पाण्डेय की मदद से बनारस की राजनीति को 'रिमोट कंट्रोल' से चलाने का प्रयास करते हैं। इन तीनों गुटों के एक होकर काम करने की कोई संभावना निकट भविष्य में तो नजर आती नहीं। ये तीनों गुट एक दूसरे की वफादारी को संदेहास्पद बनाने में भरपूर भूमिका अदा करते हैं। इसी का फल है कि वी०पी० सिंह के बनारस दौरे की सफलता के पीछे पंडितजी की सहानुभूति का शोर मचाया गया। इन्हीं सूत्रों का कहना है कि वी०पी० सिंह पंडित कमलापति त्रिपाठी के यहां चाय पर भी आमंत्रित थे, लेकिन बाद में पंडितजी ने यह कार्यक्रम मुल्तवी कर दिया। चाय पर वी०पी० सिंह को पंडितजी ने निमंत्रित किया था या नहीं—यह तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि वी०पी०सिंह के इस बनारस दौरे ने पंडितजी सहित इंका आलाकमान के ठंडे पसीने ला दिये हैं। वी०पी० सिंह द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंका के गढ़ पर धावा बोलने का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस-इ समिति में बच्चा पाठक को महामंत्री का पद दे दिया गया है। बच्चा पाठक उन लोगों में से हैं, जिनको पिछली विधानसभा में टिकट तक नहीं दिया गया था। अब ब्राह्मण-आधार अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यह टोटका किया गया है। लेकिन क्या इससे वी०पी० सिंह के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकेगा? **—दिनेश दीनू**

उपाधि और बनारस में राजा मांडा को अभूतपूर्व समर्थन मिलने से इंका का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन यह चिंता बनारस में सक्रिय तीन इंका नेताओं द्वारा दूर होती नजर नहीं आती। क्योंकि ये तीनों गुट एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हैं। इन तीन गुटों के नेता हैं—पं० कमलापति त्रिपाठी, श्यामलाल यादव और रत्नाकर पाण्डेय।

: क्लाउन

ंभावना
ये तीनों
बनाने में
ल है कि
लता के
ा गया।
ह पंडित
ामंत्रित
मुल्तवी
ंडितजी
हीं पता,
बनारस
के ठंडे
ीं उत्तर
नतीजा
ा पाठक
ा पाठक
सभा में
-आधार
या गया
े बढ़ते
दीनू

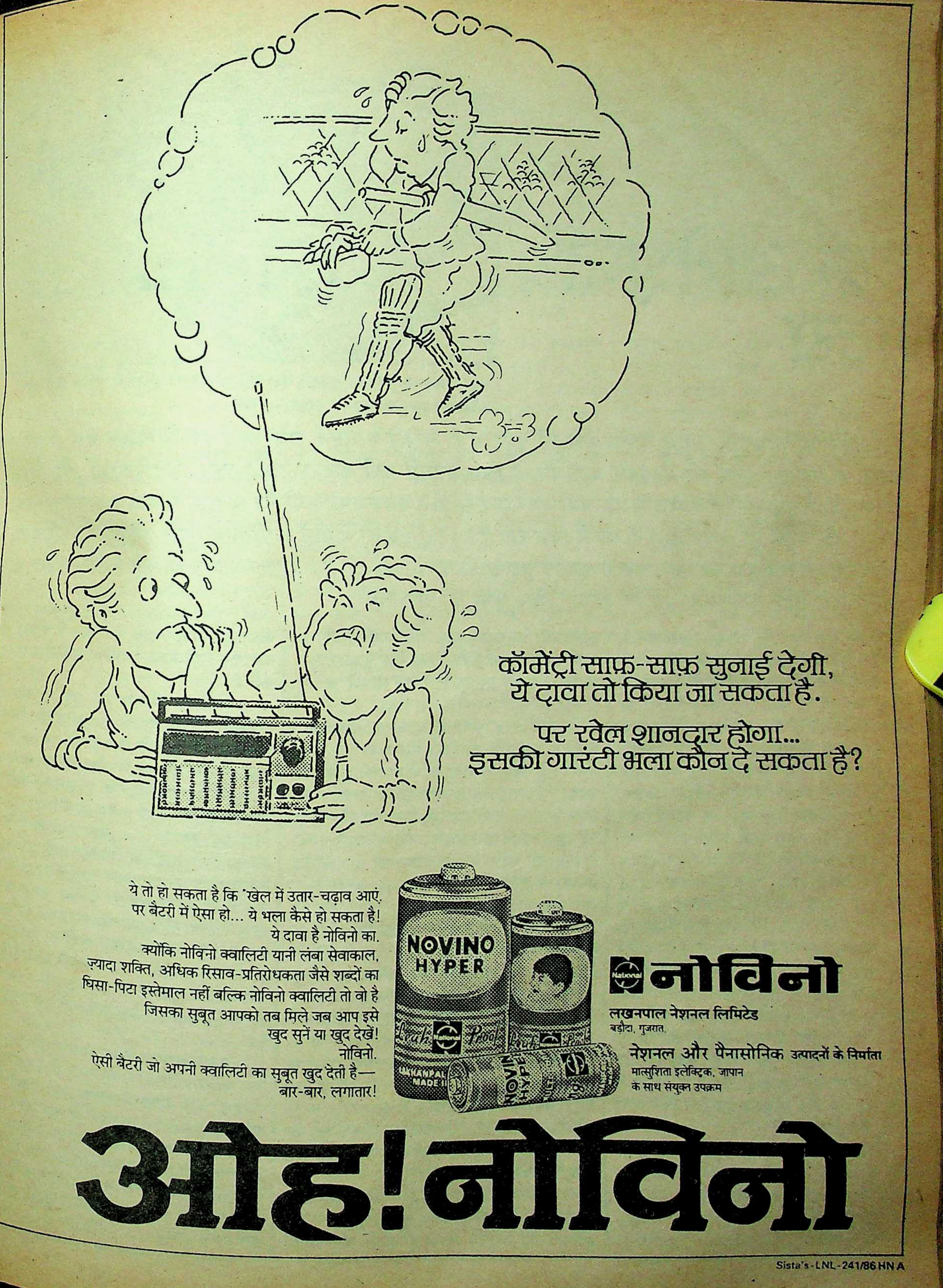

कॉमेंट्री साफ़-साफ़ सुनाई देगी,
ये दावा तो किया जा सकता है.

पर खेल शानदार होगा...
इसकी गारंटी भला कौन दे सकता है?

ये तो हो सकता है कि खेल में उतार-चढ़ाव आएं.
पर बैटरी में ऐसा हो... ये भला कैसे हो सकता है!
ये दावा है नोविनो का.
क्योंकि नोविनो क्वालिटी यानी लंबा सेवाकाल,
ज़्यादा शक्ति, अधिक रिसाव-प्रतिरोधकता जैसे शब्दों का
घिसा-पिटा इस्तेमाल नहीं बल्कि नोविनो क्वालिटी तो वो है
जिसका सुबूत आपको तब मिले जब आप इसे
खुद सुनें या खुद देखें!
नोविनो.
ऐसी बैटरी जो अपनी क्वालिटी का सुबूत खुद देती है—
बार-बार, लगातार!

National नोविनो
लखनपाल नेशनल लिमिटेड
बड़ौदा, गुजरात.

नेशनल और पैनासोनिक उत्पादनों के निर्माता
मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जापान
के साथ संयुक्त उपक्रम

ओह! नोविनो

Sista's-LNL-241/86 HN A

अकाल

एक अभिशप्त राज्य

सिर्फ भगवान का भरोसा : भगवान शिव की अर्चना करते मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और प्रदेश लोकदल (ब) अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा

इस समय भारत का दो-तिहाई हिस्सा सूखे की चपेट में है, लेकिन मानसून राजस्थान को तो पिछले चार सालों से धोखा दे रहा है। प्रदेश को नंदनवन बना देने के लिए बनायी गयी इंदिरा गांधी नहर वितरिकाओं और लिफ्ट योजनाओं के पूरा होने के अभाव में एक लंबी मगर उथली झील बनकर रह गयी है। अनाजों के दाम अनापशनाप चढ़ रहे हैं और पानी एक दुर्लभ वस्तु के रूप में बिक रहा है। ८६६७ गांवों में पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। अधिकांश शहरों में लोग भीषण पेयजल संकट से गुजरते हुए प्रदूषित जल पी रहे हैं। आसार नजर आ रहे हैं कि अकाल का भीषणतम कहर राजस्थान पर ही टूटेगा। ***ओम सैनी*** *का आकलन :*

पिछले चार साल से मानसून राजस्थान से नाराज है। इस बार भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सिर्फ बीकानेर जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, बाकी २६ जिलों में वर्षा की हलकी बौछारें पड़ीं। परिणामस्वरूप, उजड़ी खेती और बेरोजगारी के साथ-साथ प्रदेश के इक्कीस शहरों और कस्बों में पेयजल की किल्लत नजर आने लगी है। सबसे ज्यादा खराब हालात अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ के हैं, जहां ७२ घंटों में केवल तीन घंटों के लिए पानी दिया जाता है।

ब्यावर में प्रतिदिन २० लाख लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है, जबकि विभिन्न जल स्रोतों से प्राप्त हो रहा है, मात्र १० लाख पचास हजार गैलन पानी। लोग पानी उसी तरह से खरीद रहे हैं, जिस तरह अन्य जरूरत की चीजें खरीदते हैं। ट्रैक्टर से जुड़ी पानी की टंकी ७० से ९० रुपए में मिल रही है, जबकि बैलगाड़ी में ड्रमों में लादकर लाया गया पानी, दस से सोलह रुपए में बिक रहा है।

अजमेर शहर में फाय सागर और आना सागर की झीलें एकदम सूख गयी हैं। उदयपुर और जोधपुर का भी यही हाल है, इन शहरों में जल-वितरण अब एक दिन छोड़कर एक दिन किये जाने की मजबूरी आनेवाली है।

प्रांत के जलप्रदाय विभाग ने २१ शहरों को भयंकर पेयजल संकट वाला करार दिया है। इन शहरों में—माउंट आबू, आबू रोड, सोजत, जालौर, भीनमाल, सिरोही, सिवाना, भरतपुर, डीग, टोडाभीम, भीलवाड़ा, आसींद, प्रतापगढ़, कांकरोली, फतेहनगर और पाली शामिली हैं। ये शहर राज्य के उन १७४ शहरों में से हैं, जहां प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई निर्धारित मापदंड से कम हो रही है।

इसी तरह राज्य के ४ करोड़, ९५ लाख मवेशियों को पीने का पानी सुलभ कराना राज्य सरकार के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। सरकार के सहायता विभाग ने केंद्र सरकार को अलग से ज्ञापन देकर पेयजल, यातायात और कुओं को गहरा कराने तथा सितंबर तक सिंचाई व्यवस्था के लिए एक करोड़ ६२ लाख रुपए की मांग की है। सितंबर के अंत तक इन कामों पर ढाई करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड-पंपों का सहारा ले रही है; पर जलस्तर नीचे चले जाने के कारण यह सहारा भी कमजोर होता जा रहा है। मसलन, जयपुर जिले में ही जलस्तर में तीस फुट से अधिक की गिरावट हुई है। वर्ष १९८१ तक इस जिले में पानी चौदह फुट पर उपलब्ध हो जाता था। पश्चिम राजस्थान में यह स्तर १०० से १३० मीटर तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में सरकार नलकूप खोदने, उन्हें गहरा करने पर विचार कर रही है, जबकि राजस्थान में नलकूप ही जल-संकट का स्थायी निदान हो सकते हैं।

इंदिरा गांधी नहर के पूरा होने के बाद कहा जा रहा था कि अब मरुप्रदेश सूखे से मुकाबला कर सकेगा। पर वास्तव में वितरिकाओं और लिफ्ट योजनाओं के पूरे होने के अभाव में इंदिरा गांधी नहर एक लंबी मगर उथली झील जैसी बन कर रह गयी है।

सरकार जिम्मेदार: यह समस्या उस राजस्थान में है, जहां सात मरुस्थलीय जिलों में इंदिरा गांधी नहर के आगमन से पूर्व २५ से ३० मील की दूरी तय कर के लोग पीने का पानी लाते थे। पानी लाना परिवार के सदस्यों की उसी तरह जिम्मेवारी थी, जिस तरह आजीविका कमाना। आज ३४ हजार, ९६८ आबाद गांवों में से २६ हजार, ३०१ गांवों में पीने का पानी उपलब्ध है। निश्चित रूप से मानसून के धोखे ने राज्य की खेती उजाड़ी है, पर पेयजल की समस्या राज्य सरकार की असफलता की कहानी है। यह सच है कि मानसून के अभाव में जलाशय सूखे हैं, कुओं का जलस्तर घटा है, पर नलकूपों की पकड़ से पानी कभी नीचे नहीं गया। केंद्रीय भूजल मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान की धरती में कम-से-कम दस लाख एकड़ फुट पानी है।

राज्य सरकार के आला अफसरों और पिछले तथा वर्तमान नेताओं ने मरुस्थल की छाती चीरकर पानी हासिल करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि मानसून की नाराजगी ने सारी योजनाएं गड़बड़ा दीं। केंद्र सरकार ने सूखा पीड़ित राजस्थान को इक्कीस करोड़ रुपए दिये हैं जो पीने के पानी की समस्या पर नहीं, बल्कि उजड़ी खेती से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर खर्च करने होंगे।

प्रदूषित जल की प्रतीक्षा

छाया : गोपाल संगर

मीलों दूर है पानी

प्रदूषित जल : दरअसल, आज के राजस्थान में समस्या पीने के पानी की कमी से ज्यादा दूषित एवं प्रदूषित पानी की है। उदयपुर के नागरिकों ने 'कॉमन काज सोसायटी' बनाकर राज्य सरकार व जलदाय विभाग के विरुद्ध मई माह में वहां के मुंसिफ न्यायालय में दावा दायर कर गंभीर आरोप लगाये हैं। इस सोसायटी के वकीलों ने अपने वाद में कहा है कि उदयपुर में जो पेयजल बांटा जा रहा है, वह बिलकुल गंदा है और मानवीय उपयोग के काबिल नहीं है। असमय जल-वितरण तथा अपर्याप्त मात्रा पर एतराज करते हुए, इन लोगों ने अशुद्ध जल की वजह से पीलिया और उदर रोग के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। अपने कथन की पुष्टि के लिए वादीगणों ने 'राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल' द्वारा किये गये अध्ययन व उदयपुर एन्वायरमेंटल ग्रुप द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल ने वर्ष १९८६-८७ की अपनी रिपोर्ट में माना है कि उदयपुर की पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर झीलें जो नगर की जल-जरूरतों को पूरा करती हैं, शहर के अत्यधिक औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण दूषित जल का स्रोत बन गयी हैं। प्रदेश के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के विभिन्न शहरों के दूषित जल की कहानी लिखी है। मण्डल ने प्रदेश में २४० मध्यम एवं बड़े स्तर के ऐसे उद्योग नामजद किये हैं जो जल-दूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मण्डल के कानूनी दबाव से अब तक इन उद्योगों में से अस्सी ने प्रदूषित पानी शुद्ध करनेवाले ट्रीटमेंट प्लांट लगाये हैं। बाकी में से ३४ फैक्ट्रियां यह प्लांट लगाने की दिशा में अग्रसर हैं, जबकि ३६ ने लगाने का आश्वासन दिया है। शेष कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं।

राजस्थान में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल गठित हुआ, २१ अगस्त, १९८५ को, जबकि उक्त कारखाने जल दूषित करने का काम कर रहे हैं, पिछले तीन दशकों से। नतीजा यह हुआ है कि राजस्थान में पाली शहर की ४५० रंगाई-छपाई करनेवाली फैक्ट्रियां हर रोज डेढ़ करोड़ लीटर दूषित जल धरती को सोखने और प्रमुख नदी बांडी में मिलने के लिए छोड़ रही हैं। यहां राजस्थान औद्योगिक विनियोजन निगम ने १९८३ में गंदा पानी साफ करने के लिए 'ट्रीटमेंट प्लांट' लगाया था, जिसे उद्योगपतियों द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा न करवाने के कारण १९८४ में बंद करना पड़ा। राज्य प्रदूषण निवारण और नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पी०एस० राजवंशी के अनुसार अब इसे पुनः चालू किया जा रहा है और उन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है जो पर्यावरण नष्ट करने के लिए जिम्मेवार हैं।

यह वही पाली शहर है, जहां गायों को एसिड से जला देने के कारण सांप्रदायिक दंगा भड़का था। पर एसिड मिला दूषित जल पीने में यहां के नागरिकों को कोई ऐतराज नहीं है। इसी तरह जोधपुर शहर की ३९७ औद्योगिक इकाइयां हर रोज एक करोड़ लीटर दूषित जल जोजड़ी नदी में मिलने के लिए छोड़ रही हैं और बालोतरा की १२६ फैक्ट्रियां पचास लाख लीटर दूषित जल लूणी नदी में मिलाती हैं। इस दूषित जल का सीधा असर कुओं और हैंडपंपों के पानी में नजर आ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हड्डी, पेशाब तथा पेट के रोग जानलेवा बन रहे हैं।

गुलाबी नगर जयपुर के नागरिक भी शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के दुस्साहसिक प्रयोगों के कारण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जो शहर अपनी सफाई व्यवस्था के लिए विख्यात था, आज राजस्थान आवासन मण्डल और जयपुर विकास प्राधिकरण की कालोनियों के गंदे पानी के कारण वह प्रदूषित जल पीता है। आवासन मण्डल और प्राधिकरण ने अपने द्वारा बनायी कालोनियों के गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए किसी ट्रीटमेंट प्लांट का प्रबंध नहीं किया है। ज्यादातर मकानों का गंदा पानी घरेलू गटर के खड्डों में समाता है, जिसका नतीजा यह हो रहा कि कुओं में बहनेवाला पानी दूषित होने लगा है। जयपुर की १२ लाख की जनसंख्या को हर रोज १६९५ लाख लीटर पानी जलदाय विभाग द्वारा वितरित किया जाता है, जिसमें १८० लाख लीटर पान्नी रामगढ़ झील का और बाकी पानी ट्यूबवेलों का आता है। ऐसी स्थिति में प्रदूषित पानी की मात्रा जयपुर शहर के नागरिकों के हिस्से में ज्यादा आती हैं। राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल ने अपनी सन १९८६-८७ की रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि राज्य के ज्यादातर शहरों में घरों की गंदगी को ठिकाने लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उसका दावा है कि जल-प्रदूषण को रोकने के लिए २५० करोड़ रुपए की राशि काफी होगी, पर यह राशि राज्य की वर्तमान राजस्व स्थिति में जुटाना संभव नजर नहीं आता।

भगवान ही सहारा : भारतीय फिल्मों की तरह राजस्थान सरकार का सत्ताधारी दल और विपक्ष एक साथ मिलकर जुलाई माह में देवराज इंद्र की अर्चना में लगा था। चालीस साल की आजादी के बावजूद शासन के पैर आज भी प्राकृतिक विपदा के दौरान नवजात शिशु की तरह डगमगाते हैं। मिस्टर क्लीन भले ही 'हरित क्रांति' की उपलब्धियों से देश को भूखा न मरने दें, पर राजस्थान के थार की प्यास बुझाना, उनके तथा उनकी प्रादेशिक सरकार अथवा विपक्ष के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि वर्षा के अभाव में पैदा हुए सूखे से मुकाबले की योजनाएं बनाने के साथ-साथ मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और विपक्षी दलों के नेता एक साथ इंद्र और उनके सहयोगी देवताओं की पूजा-अर्चना में लगे हैं।

जयपुर के झारखण्ड महादेव के मंदिर में जुलाई माह में मुख्यमंत्री ने महारुद्राभिषेक यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी धर्मपरायण जननेताओं ने राजनीति का चोली-दामन त्यागकर उनका साथ दिया। चटखारे लेनेवाली कलमों ने इस आयोजन को संतुष्टों एवं असंतुष्टों की राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया है, पर हकीकत में यह साधनविहीनों द्वारा किसी चमत्कार की अपेक्षा से किया गया आयोजन था। अगस्त माह में राजस्थान का ऐसा कोई शहर नहीं बचा था, जहां इंद्र की आराधना राम के नाम के साथ न हो रही हो। पर बादल हैं कि बरसने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में पीने का पानी एक भीषण समस्या बन चुका है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार फिर एक बार केंद्र द्वारा भेजी सूखा अध्ययन टोली के सामने झोली फैलाकर खड़ी है। यह टोली राज्य सरकार के उन ज्ञापनों पर अपना निर्णय देगी, जिनमें राहत के लिए लगभग सात सौ करोड़ रुपए की मांग की गयी है। ■

एक अबोध बालक...

एक ज़िम्मेदार माता-पिता...

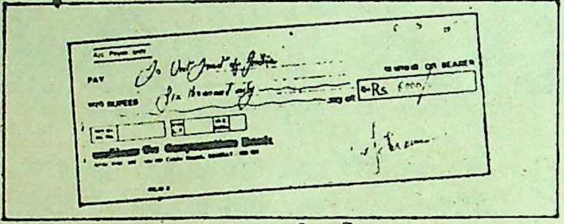

एक आदर्श योजना!

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आपके बच्चे के भविष्य की संपूर्ण सुरक्षा के लिए एक योजना - "बाल उपहार वृद्धि निधि". एक ज़िम्मेदार माता-पिता होने के नाते आप सिर्फ़ इतना कीजिए अपने बच्चे के नाम पर एक छोटीसी राशि इस योजना में निवेश कीजिए.

बच्चे के बढ़ने के साथ-साथ आपकी निवेश राशि भी 21 वर्षों में बढ़कर 12 गुना से भी ज्यादा हो जाती है! हरेक वर्ष 12.5% डिविडेन्ड और साथ में हर 5 वें वर्ष बोनस डिवीडेन्ड भी.यानी योजना की परिपक्वता पर आपके बच्चे को मिलती है बेहद उपयोगी, एक मुश्त बड़ी रकम.

वह भी ख़ास ज़रूरत के वक्त पर.जैसे की उंची शिक्षा हासिल करने, अपना कोई कारोबार शुरु करने या फिर मकान आदि खरीदने के लिए!

- कोई भी वयस्क, माता-पितां, रिश्तेदार या दोस्त 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को यह उपहार दे सकता है. एक ख़ास सुविधा के अंतर्गत आप 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे का नाम वैकल्पिक लाभ-भोगी के रूप में नामित कर सकते हैं.
- 12.5% का निश्चित डिवीडेन्ड का अपने आप ही यूनिटों में पुनर्निवेश.
- बच्चे के 18 वर्ष का होने पर रकम भुनाने या योजना से अलग होने की सुविधा.
- हर वर्ष के अंत में आपको एक विकास-तालिका (Growth Chart) भेजी जाएगी जिसमें आपके बच्चे के नाम पर मौजूद कुल यूनिट संख्या का ब्यौरा होगा.
- करों मे छूट: उपहार-कर अधिनियम (Gift Tax Act) के अंतर्गत एक वर्ष में उपहार स्वरूप दी जाने वाली 20,000 रु. तक की राशि पर कोई उपहार-कर नहीं. इस योजना के अंतर्गत यूनिट हर साल ऐसे उपहारों का एक या संपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं.
- यूनिटों से होने वाली 10,000 रु. तक की राशि (यूनिटों से 3,000 रु. तक की अतिरिक्त आय और यूनिटों तथा निवेश की कुछ अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों से 7,000 रु.) कर योग्य राशि पर आय-कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी तरह का आय-कर नहीं.

और यही है यूनिट ट्रस्ट की "बाल उपहार वृद्धि निधि!"

योजना जिसमें है आपके बच्चे के भविष्य की सुरक्षा.

21 वर्ष की उम्र में 12,000 रु. की राशि प्राप्त करने
के लिए अलग-अलग उम्र में निवेश की जाने वाली राशि.

उम्र (वर्ष)	राशि* (रु.)	उम्र (वर्ष)	राशि* (रु.)	उम्र (वर्ष)	राशि* (रु.)
जन्म के समय	1,000	6	2,100	11	3,700
1	1,200	7	2,300	12	4,100
2	1,300	8	2,600	13	4,700
3	1,500	9	2,900	14	5,200
4	1,600	10	3,300	15	5,900
5	1,800				

** रु. 100 के नज़दीकी पूर्णांक में निवेश की जाने वाली राशि.*

आवेदन फार्म किसी भी यूनिट ट्रस्ट कार्यालय,
प्रमुख प्रतिनिधि या एजेंट अथवा चुने हुए
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हैं

कृपया मुझे C.G.G.F. की मुफ़्त पुस्तिका भेजिए.
नाम: __________
पता: __________

इस योजना के अंतर्गत यूनिट साल-भर 10/- रु. प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर बेचे जाते हैं.

कूपन यूनिट ट्रस्ट को इस पते पर भेजें:
बम्बई, पोस्ट बैग 11410, फ़ोन: 256887/571995
कलकत्ता, पोस्ट बैग 60, फ़ोन: 239391
मद्रास, पोस्ट बैग 5063, फ़ोन: 27433/20938
नई दिल्ली, पोस्ट बैग 5, फ़ोन: 331 8638

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था)

APEX 87485 HIN

किधर जायेगा बिहार?

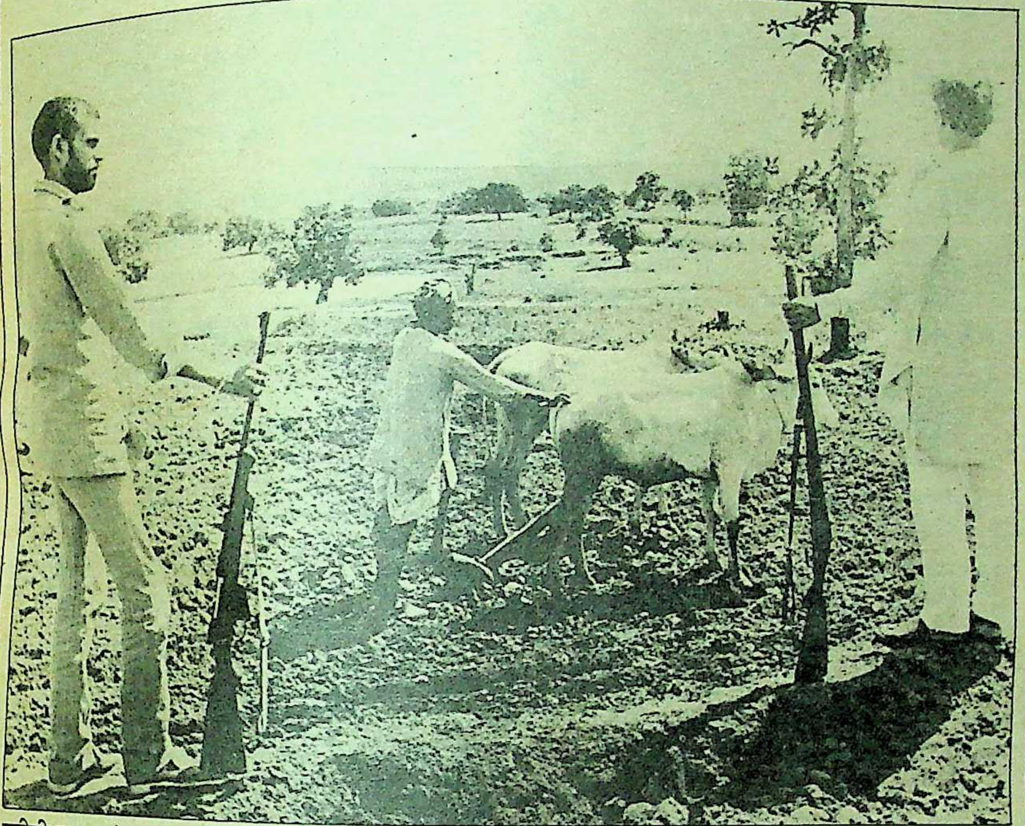

गरीबी पर आतंक का साया : कैमूर के एक गांव में खेती का एक दृश्य

अर्नाड मैंडगेरन नाम था, उस नौजवान फ्रांसीसी फिल्म डायरेक्टर का जो अगस्त माह के आखिरी दिनों में एक दोपहर अचानक 'माया' के पटना कार्यालय में पहुंचा। अपनी फिल्म के लिए वह बिहार पर कुछ विशिष्ट कार्य करने के इरादे से पटना आया था। वह बेलछी जाना चाहता था, जहां २७ मई, १९७७ को ग्यारह हरिजनों को जिंदा जला दिया गया था और श्रीमती गांधी हाथी पर चढ़कर बेलछी गयी थीं। 'माया' के छायाकार के संग वह बेलछी गया। बाढ़ में डूबी विकास से हजारों मील दूर बेलछी से जब अर्नाड लौटा, तो वहां की बदहाली को अपने कैमरे में कैद कर स्तब्ध था। साथ ही अपने उद्देश्य की कामयाबी पर संतुष्ट भी। बस उसने एक वाक्य कहा, "जीवन के सबसे दर्दनाक रूप को वहां देखा मैंने।"

पर सवाल सिर्फ बेलछी जैसे गांवों का ही नहीं, हताशा से पूरा बिहार ही गुजर रहा है। फिर एक बहुत बड़ा खतरनाक सवाल हर जागरूक बिहारी के दिमाग में कुंडली मार कर बैठ गया है कि बदकिस्मती के ढलान पर वे कब तक इस तरह फिसलते चले जायेंगे और क्या बिहार-मणिपुर और गोआ से भी पीछे चला जायेगा?

अभी कुछ सप्ताह पूर्व सरकारी हवाले से समाचार एजेंसियों ने एक खबर दी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश के सभी प्रांतों से पीछे है। आखिरी नंबर पर यतीम सा खड़ा है बिहार। आखिर क्यों, कैसे और कब तक—ये सवाल हर प्रबुद्ध बिहारी के मन को दहलाये हुए हैं।

सबसे कम आय : १९७०-७१ से १९८५-८६

बिहार को समग्र रूप से खुशहाल बना देने का वायदा और दावा करते हुए सत्तासीन होनेवाले राजनेताओं ने आजादी के ४० सालों में बिहार को बेहद दयनीय स्थिति तक पहुंचा दिया है। आज बिहार के ९१ प्रतिशत निवासी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, ७५ प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से समकक्ष राज्यों से सर्वाधिक कम बिजली बिहार में उपलब्ध है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र बिहार में है, सबसे कम चिकित्सा सुविधा बिहार में है, लेकिन राज्यों और केन्द्र सरकार में बैठे नेता इन सबसे आंखें मूंदे राजनीतिक जोड़-तोड़ में लगे हैं। क्या प्रदेश को स्वर्ग बनाने का सपना दिखानेवाले राजनेता प्रदेशवासियों को स्वर्गवासी बनाकर ही दम लेंगे?

हर साल डूबना है : बिहार में बाढ़

पं. बिन्देश्वरी दूबे
किसान सेवा सदन
शाहपुर

किसानों के नाम पर अपना नामकरण : मुख्यमंत्री का किसान सेवा सदन

के मध्य आधिकारिक आय के हिसाब-किताब के मुताबिक १९७०-७१ में प्रति व्यक्ति आय में फर्क ३.४३ हुआ। चालू दामों पर औसतन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १९८५-८६ में १५९६ रुपए थी, पर इसी वर्ष दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय ५३१५ रुपए हो गयी जो राष्ट्रीय औसत का दोगुना था। दूसरी तरफ विगत पंद्रह वर्षों में बिहार की प्रति-व्यक्ति आय में भारी गिरावट आयी है और हाल में सरकारी हवाले से प्रकाशित रपट के मुताबिक वर्ष १९८५-८६ में बिहार की प्रति व्यक्ति औसत आय महज १५४८ रुपए रही और इस तरह विकास की कतार में बदनसीब बिहार सबसे पीछे है।

प्रति व्यक्ति न्यून आय प्रदेश की पूरी अर्थ-व्यवस्था को दो तरह से झकझोरती है। सबसे पहला तो प्रति व्यक्ति कम आय का मतलब है, कम बचत, लागत और आखिरकार कम उत्पादन। कुल मिलाकर प्रतिव्यक्ति आय पूरे प्रदेश की खोखली स्थिति का चौंकानेवाला हिसाब देती है। बिहार के चर्चित अर्थशास्त्री प्रो० डी०डी० गुरु जो संप्रति ए०एन० सिन्हा इंस्टीट्यूट में अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर हैं, प्रति व्यक्ति आय के ह्रास का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि इसके तीन अहम कारण हैं। प्रदेश में आर्थिक उन्नति के लिए प्रारंभिक शर्त है, उद्योग और उत्पादन और इस सबके लिए ऊर्जा आवश्यक है। पर अन्य प्रांतों की तुलना में यहां विद्युत-ऊर्जा निरंतर कम होती गयी है। १९५०-५१ में विद्युत-व्यवस्थापन क्षमता इस प्रदेश की लगभग ३५० मेगावाट थी। उन दिनों गुजरात व महाराष्ट्र की भी व्यवस्थापन क्षमता बिहार से कुछ कम ही थी, अधिक नहीं। पर इन दिनों जहां गुजरात व महाराष्ट्र की क्षमता लगभग ५००० मेगावाट तक जा पहुंची है, बिहार १५०० मेगावाट के आसपास ही रेंग रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे ? दरअसल; विद्युत प्लांटों की अनुमति केंद्र सरकार देती और बिहार के सरकारी सूबेदार कभी इस सबकी स्वीकृति लेने में दिलचस्पी नहीं ले सके। स्पष्ट है अगर विद्युत नहीं तो उत्पादन नहीं और फिर उत्तरोत्तर प्रति व्यक्ति आय का ह्रास।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की गिरावट का दूसरा कारण मौद्रिक है। वित्तीय स्रोत तीन तरह के हैं—एक तो खुद प्रांत की सरकार जुटाये, दूसरे केंद्र की सहायता और तीसरा बैंकों के माध्यम से सुलभ सहायता। केंद्रीय सहायता जो मिलती भी है, वह 'लोन' के रूप में। उस लोन को चुकाने में ही सरकार की तबियत बिगड़ी रहती है। बैंकिंग संस्थाओं का रवैया भी बिहार को लेकर दुखद है। बिहार का जितना पैसा बैंकों में जमा होता है, उसका ५० प्रतिशत भी यहां के लोगों को ऋण के रूप में नहीं मिलता, जबकि देश स्तर पर बैंकों का कुल जमा और बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋण का अनुपात औसतन ७० प्रतिशत है। इसका मतलब साफ है कि अन्य प्रांतों में जितनी राशि बैंकों में जमा होती है, उससे कहीं अधिक राशि वहां के लोगों को ऋण रूप में दी जाती है। इस सिलसिले में बैंक के पास एक तर्क यह भी है कि बिहारियों में उद्यम की क्षमता है ही नहीं। जाहिर है, बिहार के पैसों से अन्य प्रांतों का विकास हो रहा है और बिहार हाथ-हथकड़ी बंद है। बिहार की दुर्गति का तीसरा मुख्य कारण है, राजनीतिक अस्थिरता। आजादी के बाद उन्हीं प्रांतों ने उन्नति की है, जहां नेतृत्व की स्थिरता रही है। १९५६ तक बिहार में इसी कारण बहुत से विकास कार्य हुए, क्योंकि नेतृत्व की अस्थिरता उस वक्त नहीं थी। पर १९६६-६७ के बाद अस्थिरता का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक थमा नहीं। इस राजनीतिक अस्थिरता में बिहार पर दिल्ली हावी रही और बिहार की तरक्की सिर्फ उसी समय तक हो सकी, जब तक दिल्ली में बिहार के स्व० ललित नारायण मिश्र जैसे लोग हावी थे। पर इधर, दिल्ली की राजनीति में बिहार के नेता अपने पिद्दी व्यक्तित्व के कारण बिहार का लेशमात्र कल्याण भी नहीं करवा सके।

सबसे ज्यादा अनपढ़ : आर्थिक विकास और शिक्षा के बीच एक ठोस और उद्देश्यपरक संबंध है। इसके बावजूद कुल प्रांत की ७५ प्रतिशत आबादी अभी तक अनपढ़ है, जबकि पूरे देश में ६४ प्रतिशत अनपढ़ हैं। पूरे देश की तुलना में बिहार में शिक्षा-दर का विकास १९५१-१९८१ के अंतराल में अत्यंत धीमी गति से हुआ। १९५१ में पूरे प्रदेश में ३३८.६ लाख लोग अशिक्षित थे, पर १९८१ में यह संख्या बढ़कर ५१० लाख को पार कर गयी। स्व० डा० श्रीकृष्ण सिंह के मुख्यमंत्रित्व-काल में विकास सचिव के पद पर रह चुके रणछोड़ प्रसाद कहते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय बिहार में मात्र पांच प्रतिशत लोग शिक्षित थे, पर साक्षरता जिस रफ्तार में बढ़नी चाहिए थी, वह नहीं बढ़ी।

स्वास्थ्य संसाधनों में भी बिहार का पिछड़ापन रोमांचक है। १९५२ में बिहार के अस्पतालों एवं चिकित्सागृहों में ८.३ हजार शय्या सुलभ थी। शय्या की यह संख्या बढ़कर १९८४-८५ में २१.३ हजार हो गयी। फिर भी यह पूरे देश के अस्पतालों में उपलब्ध शय्या की संख्या जो १९८४-८५ में ५२७.८ हजार थी, का मात्र साढ़े चार प्रतिशत ही थी। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह बिहार को देश की चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में कब तक कामयाबी मिलेगी, कहना मुश्किल है।

खोखली स्थिति का चौंकानेवाला हिसाब : डी०डी० गुरु

विपन्न खेती : कृषि के क्षेत्र में भी स्थिति ऐसी ही भयावह है। अब तक ३४ वर्षों में खाद्य सामग्री के उत्पादन में यों तो १२३ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसकी दर ३.६२ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भी यह प्रदेश आखिरी दर्जे पर है। इसके पीछे सिंचाई क्षमता की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। १९८४-८५ में २८.२९ लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से मात्र २१.७६ लाख हेक्टेयर का ही उपयोग किया जा सका जो प्रदेश में संपूर्ण उपार्जित सिंचाई क्षमता का मात्र ७७ प्रतिशत था, जबकि पूरे देश में सिंचाई क्षमता के इस्तेमाल का प्रतिशत ८३ था। इस तरह स्पष्ट है कि पूरे देश की तुलना में विकसित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गयी क्षमता के बीच एक गहरी खाई इस प्रदेश में है। बिजली की कमी भी पिछड़ेपन का जबर्दस्त कारण है। १९८६ तक

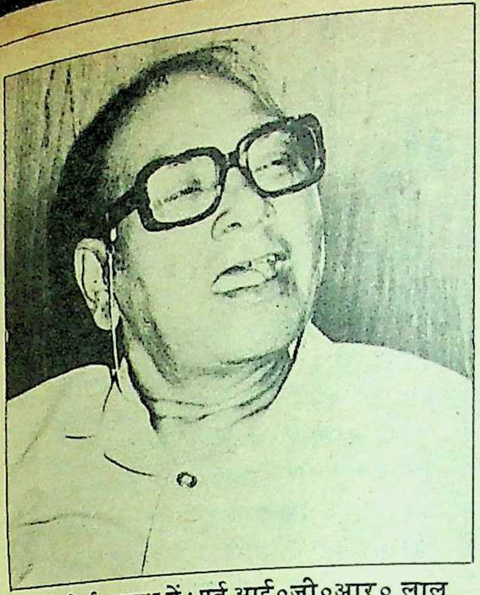

तरक्की सिर्फ अपराध में : पूर्व आई०जी०आर० लाल

प्रदेश के कुल विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत ५१.२ था, जबकि संपूर्ण भारत के विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत ६६ था।

कृषि के क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों की स्थिति दारुण है। मिसाल के लिए राज्य-फसल बीमा कोष को पायलट स्कीम के तहत ९,६६,००० रुपए १९८२-८३ में, २०,४२,००० रुपए १९८३-८४ में और ७,००,००० रुपए १९८४-८५ में दिये गये थे। १९८५-८६ में इस कोष में बची शेष राशि को एक नये कोष में स्थानांतरित कर दिया गया। पायलट स्कीम भी विफल साबित हुई है।

बढ़ती जनसंख्या : जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। नतीजतन, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बिहार की आबादी ४२८ है, जबकि पूरे देश में प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी २२९ ही है। बिलकुल साफ है कि क्षेत्रफल और आबादी की यह विषमता बिहार को तबाहियों की ओर ले जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की तादाद १९७३-७४ में ६०.७६ प्रतिशत और १९७७-७८ में ७५.०६ प्रतिशत थी और अभी १९८६-८७ में लगभग ९१.२ प्रतिशत आबादी छटपटा रही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार का प्रति व्यक्ति योजना प्रारूप (पच्चीस रुपए) अन्य तेरह बड़े प्रांतों में सबसे कम था। अन्य प्रांतों का प्रति व्यक्ति योजना प्रारूप औसतन ३८ रुपए था। यहां तक कि चौथी योजना में भी बिहार का प्रति व्यक्ति योजना प्रारूप (४८१ रुपए) जबकि अन्य १४ बड़े प्रांतों का औसत प्रति व्यक्ति योजना प्रारूप ७४७ रुपए था। बिहार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रतिव्यक्ति सिर्फ ५ रुपए केंद्रीय सहायता पायी थी। इसकी तुलना में अन्य प्रांतों को २३ रुपए औसतन मिला। पर छठीं योजना में बिहार के दिन कुछ बेहतर भी हुए। छठीं योजना में बिहार ने प्रति व्यक्ति २२४ रुपए पाये, जबकि अन्य प्रांतों का औसत २०८ रुपए रहा, फिर भी स्थिति सुधरी नहीं। बिहार का अपना राजस्व कर १९८१-८२ में सबसे कम था, महज ४८.३७ रुपए जबकि अन्य राज्यों का औसत १२२.१७ रुपए था। केंद्र से प्रति व्यक्ति बिहार को २६.४३ रुपए मिला, जबकि अन्य प्रांतों को ४०.४५ रुपए प्राप्त हुए थे। बिहार का प्रति व्यक्ति कुल राजस्व १६५.९६ रुपए था, जबकि अन्य सभी राज्यों का औसत २७३.८१ रुपए था। १९७०-७९ में बिहार का बाजार ऋण प्रति-व्यक्ति एक निराशाजनक हालात से रुबरू कराता है। बिहार बाजार ऋण से केवल ३४.५० रुपए प्राप्त कर सका जो अन्य प्रांतों के औसत ५५.३५ रुपए से कम था। बिहार का केन्द्रीय-कर अनुपात में १९८१-८२ में अन्य सभी प्रांतों से (४१.७) कम था।

अशिक्षा बरकरार : रणछोड़ प्रसाद

नानबैंकिंग संस्थाओं की प्रति व्यक्ति सहायता १९८१ में भी सबसे कम (३७ रुपए) मिली, जबकि अन्य सभी प्रदेशों को औसतन ११६ रुपए मिले। अगर हम मात्र १९७९ से १९८१ के दौरान बाह्य सहायता योजनाओं के लिए संसाधनों की बात ही लें, तो दिखायी देता है कि बिहार को उपलब्ध संसाधन (५.७६ करोड़ रुपए) न सिर्फ अन्य प्रांतों की तुलना में बिल्कुल नगण्य थे, बल्कि यह उड़ीसा (१९.६९ करोड़) से भी कम था। आज १९८७ में भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़े ही हैं।

अपराध बढ़े : बहरहाल, आंकड़ों से बिहार का जो दृश्य दिखायी देता है वह सचमुच सिहरानेवाला है। बिहार के अवकाशप्राप्त आई०जी० और संप्रति विधान परिषद सदस्य आर०लाल का कहना है कि बिहार में बस एक चीज की उन्नति हुई है और वह है, अपराध। आर्थिक आंकड़े भले ही घटते चले गये हों, पर अपराध के आंकड़ों में इजाफा ही हुआ है। १९७१ में बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की संख्या ८८७१० थी, जो दस साल बाद यानी १९८१ में बढ़कर १,१४,६९६ हो गयी। १९७१ में जहां प्रदेश में हत्या की संख्या १४०९ थी, वहां १९८६ में ३४३८ हो गयी। इस तरह अपराध में इस प्रांत ने काफी उन्नति की है। बिहार में ५ लाख से अधिक मुकदमें अदालतों में लंबित पड़े हैं, इस कारण भी अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है।

पुराने वक्त को याद करते हुए आर०लाल कहते हैं कि डा० श्रीकृष्ण सिंह के समय एल०पी० सिंह जैसे व्यक्ति मुख्यसचिव हुआ करते थे, जिनके समय सरकार का हर मुलाजिम पूरे आत्मविश्वास व निष्ठा से काम करता था, क्योंकि किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं था। मुझे याद है, एल०पी० सिंह ने बिहार में ऐसे अधिकारियों के बारे में एक गुप्त सर्वेक्षण करवाया था, जिन पर भ्रष्ट आचरण का महज संदेह था। उस समय वरिष्ठ अधिकारियों में भ्रष्ट आचरण के मात्र दो-तीन लोग पाये गये थे। पर आज स्थिति ठीक विपरीत है, अच्छे आचरण के अधिकारी दो-तीन भी मिलना मुश्किल है। पुलिस का भी मनोबल तोड़कर रख दिया गया है। एक एस० पी० को छह माह से अधिक किसी जिले में टिकने ही नहीं दिया जाता। ऐसे में प्रशासन की क्या परिकल्पना की जाये।

दोष बिहारियों का : सुधा सिन्हा

फिर से सवाल वहीं आकर ठिठकता है, ऐसा कब तक ? पर इसका जवाब न तो निर्लज्जतापूर्वक सिंहासन पर डटे मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे के पास है, न इंका के विद्रोही तेवर के नेता डा० जगन्नाथ मिश्र के पास और न ही विपक्षी राजनीति के जागीरदार कर्पूरी ठाकुर के पास। बिन्देश्वरी दुबे को अपना पद बचाने की फिक्र है, जगन्नाथ मिश्र को पद पाने की और कर्पूरी की सारी प्रतिभा इसी जोड़-तोड़ में खतम हो रही है कि कब तक वह विधान सभा में विरोधी दल के नेता पद की सुविधा उठा पाते हैं। आम आदमी हतप्रभ है। उसकी झोली में सिवा हताशा के कुछ भी नहीं। देश-विदेश के पत्रकार बिहार में गुलीवर की मुद्रा में आते हैं और 'बौने प्रदेश' की चलताऊ रपट लिखकर छुट्टी पा लेते हैं। बिहार की बदहाली अखबार और पत्रिकाओं में ऊंची कीमत पर बिक जाती है, पर बिहार का आदमी साल-दर-साल बद से बदतर

होता जा रहा है।

वह भी जानता था : बिहार का राजनीतिक कलुष इस सबके पीछे खतरनाक भूमिका निभा रहा है। आजादी के तत्काल बाद के मुख्यमंत्री डा० श्रीकृष्ण सिंह और उन्हीं की काबीना के वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक विरोधी थे, पर दोनों ने मर्यादा की सीमा कभी नहीं लांघी। पुराने लोग बताते हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह अगर कोई आदेश कर देते थे, तो मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह तमाम कटुता के बावजूद उसे यथावत रहने देते थे। पर १९८७ की राजनीति के नेता बिन्देश्वरी दुबे और डा० जगन्नाथ मिश्र हैं। बाढ़ की तबाही में दुबे झंझारपुर में राहत कार्य इसलिए नहीं होने देते, क्योंकि वह क्षेत्र जगन्नाथ मिश्र का है। जगन्नाथ मिश्र भी बस इस्तीफे की धमकी देकर रह जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते। जनता चाहे दुश्मन के चुनाव क्षेत्र की हो, इस हद की नीचता किसी मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शर्मनाक है। जनता बिहार की है, न कि बिन्देश्वरी दुबे या जगन्नाथ मिश्र की व्यक्तिगत संपत्ति कि आपसी रंजिश में निरीह जनता को घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाये, पर बिहार में यही सब कुछ हो रहा है। बाढ़ राहत के नाम पर राजीव गांधी ने मुक्त हस्त से असम व पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए देने का ऐलान किया, पर बाढ़ व सूखे, दोनों प्राकृतिक आपदा से चीथड़ा हो चुके बिहार को महज ५० लाख रुपए दिया जाना तय हुआ। इसके तत्काल बाद जगन्नाथ मिश्र का एक वक्तव्य भी छपा कि मात्र इतनी राशि मिलना बिहार के साथ अन्याय है, पर अगले ही दिन उन्होंने इसका खंडन किया कि उन्होंने यह नहीं कहा कि मात्र ५० लाख राहत के लिए मिलना बिहार का अपमान है। जाहिर है, जगन्नाथ मिश्र भी अब उसी हद तक आलोचना कर रहे हैं, जहां तक उनका नुकसान न हो। बिन्देश्वरी दुबे की बूढ़ी आंखें तो खैर इस तबाही की करुणा को देख ही नहीं सकतीं। दिल्ली की काबीना में बैठे बिहार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामानंद यादव और केंद्रीय राज्यमंत्री रामदुलारी सिन्हा या कृष्णा शाही का वह व्यक्तित्व ही नहीं कि बिहार के कल्याण के लिए लेशमात्र भी कुछ कर सकें।

क्या बिहार के लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से जी चुराते हैं और जरूरत से अधिक दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का बीजारोपण क्या उनमें बचपन से ही हो जाता है? इस विषय पर शोध कर रही ए०एन० सिन्हा इंस्टीट्यूट में मनोविज्ञान विषय की रीडर सुधा सिन्हा कहती हैं कि बिहारियों में 'होम सिकनेस' ज्यादा है। बिहार के लोग अन्य किसी प्रांत में अपने को उतनी सहजता से नहीं खपा पाते। मेहनत मजदूरी करने भी जाते हैं, तो दो चार माह बाद वहां से बोरिया-बिस्तर समेट कर लौट आते हैं। सुधा सिन्हा के मुताबिक मध्यमवर्गीय परिवार के लोगों में यह प्रवृत्ति ज्यादा है।

छाया : विक्रम कुमार, अमरेंद्र दुबे, सुधांशु

—विकास कुमार झा

डा० रमेश पाण्डेय

राजनीति के पालने में दामाद के पांव

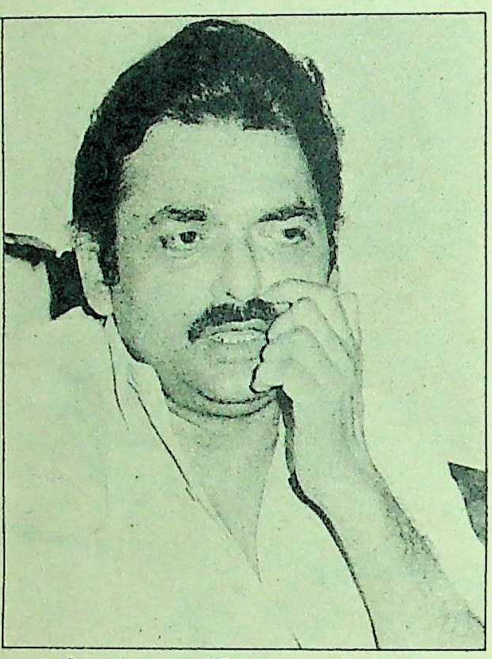

श्वसुर के बल पर राजनीति? : डा० रमेश पाण्डेय

क्या मुख्यमंत्री दुबे के इकलौते दामाद डा० रमेश पाण्डेय ने राजनीति के पालने में पांव हिलाना शुरू कर दिया है? राजनीति में आने के लिए उन्हें कैसी 'सद्भावना' और कैसा 'जनादेश' चाहिए?

उड़ीसा के बहुचर्चित मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक के दामाद सौम्यरंजन पटनायक और बिहार के मशहूर मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के इकलौते दामाद डा० रमेश पाण्डेय का न तो आपस में किसी किस्म का परिचय है और न ही कोई मुलाकात, लेकिन पटना के राजनीतिक गपोड़ियों का तुक्का है कि रमेश हू-ब-हू सौम्यरंजन की नकल पर चल रहे हैं। दरअसल, इस शिगूफेबाजी के पीछे कुछ ठोस उदाहरण भी हैं। रमेश और सौम्यरंजन में फर्क बस इतना ही है कि सौम्यरंजन पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्याता थे और रमेश एम०बी०बी०एस० की पढ़ाई निपटाकर कुछ दिन तक तो अस्पताल की नौकरी में रहे और फिर बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर बोकारो में प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे। अपने श्वसुर जानकी वल्लभ के राजकाज में सौम्यरंजन ने जिस तरह नौकरी को तिलांजलि देकर उड़िया दैनिक 'संवाद' का प्रकाशन शुरू किया, उसी तरह रमेश भी अगले माह से दैनिक 'जनादेश' का संपादन शुरू करने जा रहे हैं। 'संवाद' की शुरुआत के समय अखबार के लिए श्वसुर की मदद से हासिल जगह और विज्ञापनों को लेकर सौम्यरंजन की जिस तरह खिचायी हुई थी, इन दिनों रमेश की भी हो रही है। पर राजनीतिक तुक्कड़ों का कहना है कि रमेश, सौम्यरंजन से ज्यादा सयाने हैं। अब तक वह दुबे दरबार के नेपथ्य के शक्तिशाली सूत्रधार थे, पर आनेवाले लंबे वक्त की राजनीति के रसद-पानी का इंतजाम करने के लिए रमेश राजनीतिक रंगमंच तक जोरशोर से आने की तैयारी में भिडे हैं। अपने श्वसुर की ज्यादा उम्र को देख रमेश समझते हैं कि उनकी राजनीति बमुश्किल चार-पांच सालों की है। इसलिए भविष्य की राजनीति में अपने लिए कारगर ढंग से जमने का जुगाड़ उन्हें अभी से कर लेना होगा। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री दुबे के एक दामाद और उनकी पुत्री का दुखद निधन कई माह पूर्व एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। लिहाजा, रमेश पाण्डेय मुख्यमंत्री के इकलौते दामाद हैं और हर तरह से दुबे के उत्तराधिकारी भी।

'सद्भावना' का गठन : तकरीबन दो साल तक राजरंग को अच्छी तरह भांप-समझ कर रमेश ने अब धीरे-धीरे राजनीति की बागडोर को छूना शुरू कर दिया है। दैनिक पत्र के अलावा बिहार में बाढ़ के मौके पर उनके द्वारा तत्काल गठित स्वयंसेवी संस्था 'सद्भावना' ने इसका संकेत दिया है। राजनीतिक गली-कूचों में रमेश के 'सद्भावना' की सरगर्मी है। "२० अगस्त को राजीव गांधी के जन्म दिवस को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया गया, तो हम कुछ मित्रों के मन में विचार कौंधा कि आज की ही इस शुभ घड़ी में क्यों न 'सद्भावना' की स्थापना की जाये"—'सद्भावना' के उद्भव का खुलासा करते हुए कहते हैं रमेश। रमेश खुद 'सद्भावना' के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष पद पर पत्रकार अरुण रंजन और मुख्यमंत्री दुबे के तीन माह तक प्रेस एडवाइजर रह चुके और सम्प्रति दैनिक 'आज' के युवा स्थानीय सम्पादक सत्य प्रकाश असीम हैं। 'सद्भावना' के दो महासचिव हैं—पूर्व उपमंत्री रंजीत सिन्हा और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा तथा कोषाध्यक्ष हैं हाल में मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नामजद हुए पी०एन० पाठक। 'सद्भावना' के गठन के तत्काल बाद रजिस्ट्रेशन भी हो गया और बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्य

बाढ़
सद्भाव
ए ३/५ बेली रोड, पटना

जनसेवा से शुरुआत : बाढ़ पीड़ितों के लिए 'सद्भावना' के कपड़े

की 'सद्भावना' शुरू हो गयी। संस्था का मुख्यालय संजय गांधी जैविक उद्यान के सामने सरकारी आवास ए-३/५ बेली रोड में बिठा दिया गया। 'सद्भावना' ने एक क्रांतिकारी अपील भी जारी की—"उत्तर बिहार के २० जिलों में हजारों गांवों की एक करोड़ आबादी अपनी उदास आंखों से दूर-दूर तक सिर्फ सैलाब का खौफनाक दृश्य देख रही है। 'सद्भावना' खाद्य, कपड़ा, माचिस, मोमबत्ती, बच्चों का दूध या दवा जो भी हो, बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

आलोचना : 'सद्भावना' को लेकर दुबे के विरोधियों ने आरोप लगाने शुरू कर दिये कि बड़े ठेकेदार व इंजीनियरों से 'सद्भावना' के नाम पर तगड़ी वसूली हो रही है। पर, रमेश का कहना है कि आरोप लगानेवाले सुबह से रात तक हमारे साथ बैठें और देखें कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और कैसा अपार जनसहयोग हमें मिल रहा है। रमेश के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से उनकी 'सद्भावना' जूझेगी।

क्या यह सब राजनीतिक चक्कर नही है? रमेश बड़ी सफायी से इस सवाल को टालते हुए कहते हैं, "हमारी आकांक्षा है कि मदर टेरेसा हमें आशीर्वाद दें, ताकि उनके पदचिन्हों पर हम और हमारी 'सद्भावना' चले। राजनीति में आने का तो कोई सवाल ही नहीं।"

एक राजनीतिक अखाड़िये का कहना है कि राजनीति के पालने में दामाद के पांव ढंग से पड़ रहे हैं, इसलिए राजीव गांधी के जन्मदिवस पर 'सद्भावना' की स्थापना से लेकर मदर टेरेसा से आशीर्वाद तक की आकांक्षा की चिकनी-चुपड़ी बातें रमेश कर रहे हैं।

"हां, मैं दैनिक निकालने जा रहा हूं और इसके संपादन का भार भी मैं संभालूंगा, पर अखबार को कृषि भवन में स्थान आवंटन को लेकर जो आरोप लगाये जा रहे हैं, वे बिलकुल पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। संबधित विभाग ने कृषि भवन में लीज के लिए अखबारों में विधिवत विज्ञापन दिया था। किसी ने हमारे सिवा उसके लिए आवेदन नहीं दिया, सो जगह हमें मिल गयी। उसके सारे कागजात हैं। कहीं अनियमितता नहीं हुई"—रमेश ने 'माया' को बताया।

दिल्ली तक शिकायत : दरअसल, रमेश के दैनिक को जिस तरह नवनिर्मित सरकारी भवन में जगह मिली है, उसको लेकर दुबे—विरोधियों ने दिल्ली-दरबार को लंबा-चौड़ा ज्ञापन भी भेजा है कि एक सरकारी इमारत में कैसे किसी व्यक्ति को लीज पर जगह दे दी गयी। दुबे पर हमला करने के लिए रमेश एक जरूरी मुद्दा बनते जा रहे हैं। धनबाद में दुबे के एक चेले पारसनाथ तिवारी 'दैनिक अमृतवर्षा' का प्रकाशन करते रहे हैं। शुरू में वह यह अखबार बोकारो से निकालते थे। पर कर्मचारियों से विवाद के कारण पारसनाथ 'अमृतवर्षा' को उठाकर धनबाद ले आये। इधर 'अमृतवर्षा' का पटना संस्करण निकालने की योजना बनी। इसके तत्काल बाद ही 'अमृतवर्षा' के धनबाद कार्यालय के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा खड़ा किया कि धनाभाव का बहाना बना कर, जब उन सभी को तमाम जरूरी सेवा-शर्तों से वंचित रखा जा रहा है, ऐसे में पटना संस्करण का प्रकाशन आखिर किन पैसों से होगा। लिहाजा, आखिरकार तय यह हुआ कि 'अमृतवर्षा' को पटना से न बरसाकर, किसी दूसरे नाम से अखबार निकाला जाये। रमेश कहते हैं कि पटना से प्रकाशित एक-दो अखबारों को छोडकर अधिकांश अखबार पर किसी-न-किसी का ठप्पा है। हमारा अखबार बिलकुल सौ फीसदी ऐसे ठप्पों से मुक्त रहेगा। बहरहाल, रमेश की 'सद्भावना' और शीघ्र प्रकाश्य 'जनादेश' अभी बिहार राजनीति की 'हेडलाइन' बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री बनने के पूर्व जब दुबे प्रदेश इंका के अध्यक्ष थे, उसी समय से रमेश का नाम पटना के राजनीतिक गलियारों में गूंजा। सदाकत आश्रम के पिछवाड़े एक कमरे में रमेश के मुलाकातियों की भीड़ लगी रहती थी। दुबे जब मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठे, तो मुख्यमंत्री निवास के भीतर रमेश ने प्राकृतिक शोभा से आच्छादित कुटिया बनवायी और रमेश के मुलाकाती वहीं जमाव करते थे, पर रमेश के एक मित्र कहते हैं—"रमेशजी ने अब वह कुटिया त्याग दी है। अब वह वहां नहीं बैठते।"

क्या अगले चुनाव में सचमुच रमेश भी चुनाव मैदान में उतरेंगे या अभी कुछ साल श्वसुर के राजकाज में परोक्ष योगदान देते रहेंगे? ये और ऐसी कई अटकलें राजनीतिक तीरंदाजों को परेशान किये हुए है। पर इन तमाम प्रसंगों का रोचक समापन करते हुए दुबे दरबार के एक 'प्यारे भाई' कहते हैं—"भई, राजनीति में आने के लिए रमेश को पहले 'जनादेश' और 'सद्भावना' चाहिए, फिर देखिए।"

छाया : सुधांशु

—विकास कुमार झा

सन '४२ की वापसी

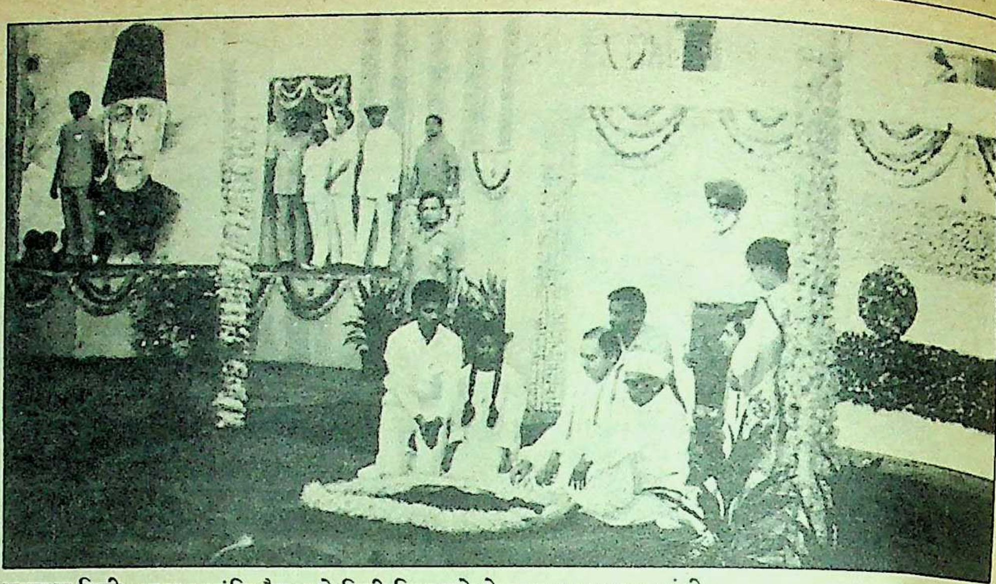

आराध्य मिट्टी : अगस्त क्रांति मैदान से मिट्टी निकालने के अवसर पर प्रधानमंत्री

अगस्त क्रांति की ४५वीं वर्षगांठ उत्साह और उल्लास का अवसर होना चाहिए था, लेकिन ९ अगस्त, १९८७ को इस समारोह के अवसर पर वैसा ही हिंसक दृश्य उपस्थित हो गया, जैसा १९४२ में पैदा हुआ था। राष्ट्रीय एकता और सम्मान का प्रतीक यह अवसर दलगत राजनीति का शिकार क्यों बना ?

बंबई का प्रख्यात ‘अगस्त क्रांति मैदान’ १०२ वर्ष पहले १८८५ में तथा ४५ वर्ष पहले १९४२ में भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन गया था। १८८५ में इस मैदान के सामने स्थित तेजपाल हाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और १९४२ में महात्मा गांधी ने ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन की घोषणा कर स्वातंत्र्य आंदोलन को एक ऐसी प्रभावशाली दिशा दे दी थी, जिसने बकिंघम पैलेस (लंदन) के गोरे हुक्मरान को यथाशीघ्र भारतवर्ष की जमीन से अपना बोरिया बिस्तर बांधने के बारे में सोचने के लिए विवश किया था।

विडंबना की बात तो यह है कि ‘अगस्त क्रांति’ की ४५वीं वर्ष गांठ के अवसर पर भी यह मैदान बजाय उल्लास-उत्सव के हिंसा का क्षेत्र बन गया। ९ अगस्त, १९८७ को इसी मैदान के सामने का हिस्सा (नाना चौक) रणक्षेत्र बन गया था। रणांगण तो ४५ वर्ष प्रहले इसी दिन यह पूरा क्षेत्र बन गया था, लेकिन तब और अब में पूर्व-पश्चिम का फर्क था। ९ अगस्त, १९४२ को इस रणक्षेत्र में एक पक्ष (पुलिस) दूसरे पक्ष (स्वातंत्र्य सेनानियों) पर डंडे, लाठियां बरसा रहा था और अश्रुगैस से पूरा इलाका धुआंसा हो गया था। लेकिन ९ अगस्त, १९८७ को इस रणक्षेत्र के सेनानी थे—भाजपा एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता।

झड़प : गाली-गलौज से शुरू दोनों राजनीतिक पार्टियों की झड़प तुरंत मल्लयुद्ध में बदल गयी—दोनों ने एक-दूसरे के झंडे छीन कर फाड़ फेंकने के बाद झंडों के डंडों से एक-दूसरे पर फिल्मी शैली में प्रहार शुरू कर दिया। अंततः दोनों पक्षों के रणबांकुरों को, तमाशा देख रही पुलिस ने अलग करने की कोशिश की और नाकामयाब होने पर तीसरी पार्टी बन कर उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं।

“घोर कलयुग आ गया है,” १९४२ में सतारा जिले में समानांतर सरकार स्थापित करनेवाले ७३ वर्षीय स्वातंत्र्य सेनानी नाथाजी लाड ने क्षुब्ध स्वर में ‘माया’ से कहा, “१९४२ को जब इसी मैदान में महात्मा गांधी ने समूचे देश को स्वातंत्र्य आंदोलन में कूद पड़ने के लिए आह्वान किया था, तो मैं भी यहां मौजूद था। पुलिस की लाठियां भी खायी थीं। अश्रु गैस से मेरी आंखें खराब हो गयी थीं, जिसका असर महीनों तक बना रहा। तब हमने लाठियां खायी थीं विदेशी हुक्मरानों की पुलिस से। उनसे लड़े भी थे गांधीवादी तरीके से। लेकिन ये लोग भला किससे लड़ रहे हैं और किस मकसद के लिए ?

बदले हुए अर्थ : १९४२ के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की ४५वीं वर्षगांठ अगस्त क्रांति मैदान (इसी आंदोलन के फलस्वरूप इस मैदान का नाम ‘अगस्त क्रांति मैदान’ पड़ा) में ९ अगस्त १९८७ को मनाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशेष रूप से बंबई आये। १९४२ तथा १९८७ में ४५ वर्षों के अंतराल में इस मैदान में हुई दोनों सभाओं में कई समानताएं थीं, लेकिन दोनों के अर्थ बदल गये थे। दोनों समारोहों की सदारत करनेवाले ‘गांधी’ थे—महात्मा गांधी एवं राजीव गांधी। दोनों बार बंबइया बरसात ने सभा के दौरान अपने जलवे दिखलाये थे और बरसात तथा भीड़ के कारण सड़क पर एकत्र कीचड़ में लथपथ तथा बारिश में भीगे लोगों पर पुलिस ने जम कर लाठियां बरसायी थीं। १९४२ में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी और सभा में उपस्थित लोगों तथा समूचे देश को गुलामी के खतरे से आगाह करते हुए एकजुट हो स्वातंत्र्य समर में कूद पड़ने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने पुराने अंदाज में देश पर मंडराते बाहरी खतरे से आगाह करते हुए राष्ट्रीय एकता की जरूरत पर बल दिया।

इस श्रद्धांजलि समारोह में अरुणा आसफ अली, पी०के० सावंत सहित कई स्वातंत्र्य सेनानी, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से एकत्र हुए थे, जिन्होंने १९४२ में अगस्त क्रांति मैदान की सभा में भाग लिया था। १९४२ में अगस्त क्रांति मैदान में भाषण देने के बाद जब पुलिस ने महात्मा गांधी तथा प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो मैदान में तैनात पुलिसवालों की आंखों में धूल झोंककर तथा उनकी घेरेबंदी तोड़कर युवा अरुणा आसफ अली ने पूरी दिलेरी के साथ तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की थी। उन्हीं अरुणा आसफ अली को ४५ वर्ष बाद इस समारोह में तिरंगा फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास समय नहीं था कि वह पारंपरिक ढंग से उनका सम्मान कर पाते या अपना कुछ ‘कीमती समय’ उन्हें दे पाते। समारोह समाप्त होने के बाद जब वह सीढ़ियां उतरने लगे, तो अचानक याद आने (या सोनिया गांधी के याद दिलाने) पर वह वापस मंच पर आये और अरुणा आसफ अली से मिले।

तीन विभिन्न प्रसंग : यह समारोह तीन विभिन्न प्रसंगों से जुड़ा हुआ था—भारत छोड़ो आंदोलन की ४५वीं वर्षगांठ, आजादी की ४०वीं वर्षगांठ तथा पं० जवाहरलाल नेहरू शताब्दी समारोह का इसी ऐतिहासिक मैदान से शुभारंभ। लेकिन बंबई के विरोधी दलों ने इसे, इस पवित्र स्थल को, राजीव गांधी एवं उनकी कांग्रेस द्वारा अपवित्र कर दिये जाने की संज्ञा दी तथा मुख्य समारोह का

बहिष्कार किया। जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता मोरारजी देसाई, समाजवादी नेता एस०एम० जोशी के अलावा सभी प्रतिपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्य समारोह का बहिष्कार कर अलग से अपने समारोह आयोजित किये। प्रधानमंत्री राजीव गांधी समारोह स्थल से चले जाने के बाद जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जुलूस एस०एम० जोशी के नेतृत्व में १०.१५ बजे अगस्त क्रांति मैदान पहुंचा और गांधी स्मृति स्तंभ पर पुष्प अर्पित किये। उनके साथ मधु दंडवते, निहाल अहमद, मृणाल गोरे, सुरेंद्र मोहन, प्रमिला दंडवते आदि भी थे।

शाम को ४ बजे वातावरण का समूचा रंग ही जैसे बदल गया। अ०भा० विद्यार्थी परिषद के ६०० से भी अधिक छात्र-छात्राएं जिनमें लड़कियों की संख्या सर्वाधिक थी तथा भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने जुलूस लिये अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे, जहां उनका सामना करने के लिए युवा कांग्रेस कर्ता पहले से ही तैनात थे। दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ सिर्फ एक-दूसरे का झंडा फाड़ने, 'सी०आई०ए० एजेंट' तथा 'बोफोर्स के दलाल' जैसे नारों के वाक्-युद्ध तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ईंट-पत्थर, लाठियों के साथ-साथ सोडा वाटर की बोतलों का भी खुलेआम प्रयोग किया गया। अंततः पुलिस को पुनः लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा।

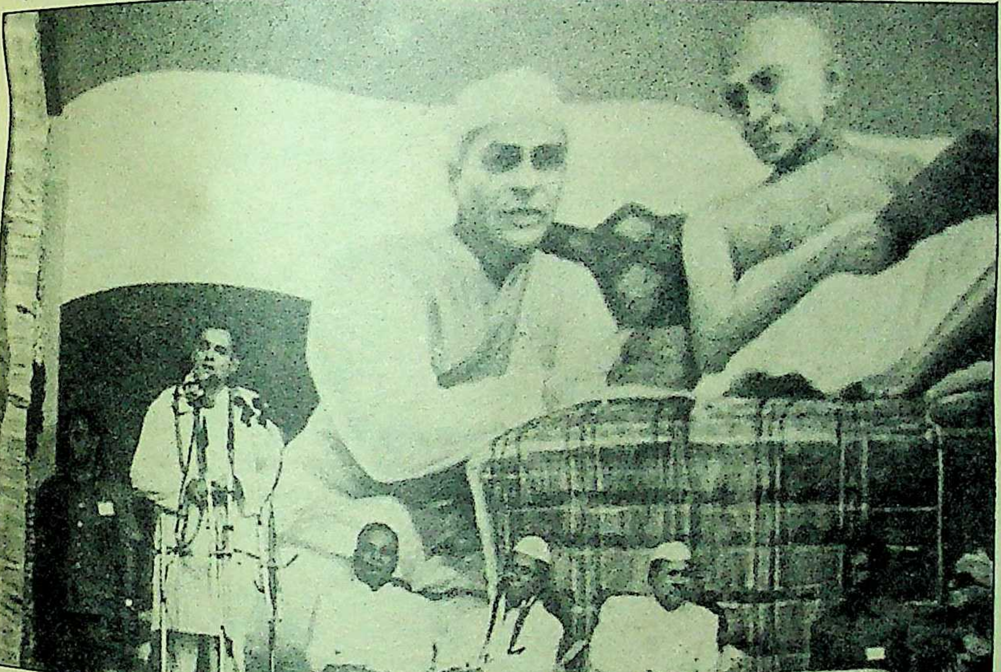

कल और आज : क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री

परिषद के सदस्यों ने क्रांति स्तंभ की घेरेबंदी कर, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अयोग्य घोषित करते हुए, क्रांति स्तंभ की बाकायदा नये सिरे से सफायी-धुलायी कर, वहां पर नये सिरे से पुष्प अर्पित किये गये। प्रख्यात समाजसेविका एवं चिंतक दुर्गा भागवत परिषद के अध्यक्ष अशोक मोडक, भाजपा नेता प्रमोद महाजन तथा हशु अडवानी ने प्रातःकालीन मुख्य समारोह में राजीव गांधी तथा दूसरे नेताओं द्वारा क्रांति स्तंभ पर चढ़ाये गये फूलों को यह कह कर वहां से फेंक दिया कि इन लोगों ने फूल चढ़ा कर इस पवित्र स्तंभ को अपवित्र कर दिया, इसलिए हमें इसका शुद्धिकरण करना पड़ रहा है।

दोनों पक्षों के खुले युद्ध तथा पुलिस के लाठी चार्ज के फलस्वरूप तीनों पक्षों के काफी लोग हताहत हुए। भाजपा की युवा शाखा के प्रभारी मनोहर प्रभाकर की बायीं आंख तथा कई नेताओं के हाथ बुरी तरह से जख्मी हुए और नायर अस्पताल में भर्ती कई घायल दूसरे दिन तक अचेत पड़े रहे।

गलत पुनरावृत्ति : सांगली (बिलारी) के वयोवृद्ध क्रांतिकारी दत्तात्रेय लोहार (७५ वर्ष) ने 'माया' को बतलाया, "४५ वर्षों में कुछ भी नहीं बदला। भाजपा तथा कांग्रेसियों के आपसी युद्ध और पुलिस के लाठी चार्ज को देखकर सन, '४२ की याद आ गयी और लगा जैसे ९ अगस्त, १९४२ की पुनरावृत्ति गलत ढंग से हो गयी है। मैं कांग्रेस सरकार की नीतियों का कड़ा विरोधी हूं, लेकिन हमारे विरोधी दलों ने इस ऐतिहासिक दिन को भी अपनी गंदी राजनीति से नहीं बख्शा।

क्रांतिकारी लालसेना के सदस्य डब्ल्यू० जी० गांवडे भी इस कांड से क्षुब्ध थे। उन्होंने १९४२ में नागपुर में तीन दिनों तक अंग्रेज हुक्मबरदारों का शासन ठप्प कर दिया था। उन्होंने 'माया' को बतलाया, "सरकार को हम क्रांतिकारियों की तो कभी परवाह रही ही नहीं, विरोधी दलों को भी नहीं रही। हर कोई पिछले ४० वर्षों से सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर रहा है।"

९ अगस्त, १९८७ के हादसे का तनाव एक सप्ताह बाद स्वाधीनता दिवस तक इस हद तक बना रहा कि एस०एम० जोशी को यह स्पष्ट करना पड़ा कि भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुठभेड से उनकी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने 'माया' को बतलाया, "मैंने तो राजीव गांधी के कार्यक्रम का बहिष्कार सैद्धांतिक आधार पर किया था। उन लोगों को ४५ वर्ष बाद देशभक्तों की कुर्बानी और अगस्त क्रांति मैदान की याद आयी। हम तो हर वर्ष यहां एकत्र होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनका कार्यक्रम खतम हो जाने के बाद जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुलूस १०.१५ बजे अगस्त क्रांति मैदान पहुंचा। हमारे जुलूस में भू०पू० मंत्री मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता निहाल अहमद, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते आदि भी थे। हमारा जुलूस शांतिपूर्ण रहा। आप वहां पर मौजूद पुलिसवालों से पूछ लीजिए कि क्या उन्हें एक बार भी टोकने का मौका मिला? भाजपावालों ने या दुर्गा भागवत ने हमारे चढ़ाये फूलों को हटाकर वहां पर सफायी क्यों की? इसके बारे में तो आप उन्हीं से पूछिए, मुझे कुछ पता नहीं।"

सांसद गुरुदास कामत ने भी दुर्गा भागवत की आलोचना की कि वह मराठी की अग्रणी लेखिका एवं बुद्धिजीवी हैं। राजनीति से, वह भी इस तरह की राजनीति से खुद को जोड़ने की भला क्या जरूरत थी? दुर्गा भागवत ने इन आरोपों की चर्चा चलने पर 'माया' को बतलाया, "मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पवित्र क्रांति स्तंभ पर से तथाकथित कांग्रेस नेताओं और उनके नेता प्रधानमंत्री, जिनके हाथ बोफोर्स की दलाली-कांड में गंदे हो गये हों, के चढ़ाये गये फूलों को फेंककर मैंने उस स्थल का शुद्धिकरण ही किया है। मेरा किसी पार्टी से लेना-देना नहीं है।"

कारण बोफोर्स : प्रतिपक्षी दलों का सारा गुस्सा बोफोर्स कांड को लेकर था। बंबई महानगरपालिका की विशेष बैठक में भी अगस्त क्रांति मैदान कांड को लेकर कांग्रेस तथा दूसरे दलों के बीच झड़प हुई। भाजपा नेता पुष्पा वागले द्वारा राजीव गांधी को 'भ्रष्ट' कहने तथा उनके साथियों द्वारा 'राजीव गांधी चोर है' का नारा लगाने पर कांग्रेस पार्षदों ने न केवल कड़ा रुख अपनाया, बल्कि इस कांड को विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की। भाजपा पार्षद राज पुरोहित का कहना था, "उस दिन (९ अगस्त, १९८७) सचमुच ९ अगस्त, १९४२ का दृश्य उपस्थित हो गया था। उसे देखकर सचमुच बापू की आत्मा काफी दुखी हुई होगी। क्या यह कम विडंबना की बात नहीं है कि १९६५ में राष्ट्र की रक्षा के लिए (स्व०) प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर भारतीय महिलाओं ने अपने मंगल सूत्र तक सरकार को दान में दे दिये थे, उसी राष्ट्र का एक और प्रधानमंत्री हथियारों की सौदेबाजी में दलाली के आरोप का शिकार है।"

भाजपा और कांग्रेस—दोनों पार्टियां पुलिस लाठीचार्ज की जांच की मांग कर अपने-अपने दामन को पाक साफ करते हुए सारे मामले की जिम्मेदारी पुलिस पर थोप कर अलग हो जाना चाहती हैं, लेकिन ९ अगस्त, १९८७ को सन, १९४२ की याद को विकृत रूप में पेश कर जो थोथी राजनीति का गहरा जख्म आजादी के पवित्र अध्याय पर चस्पां किया है, उसे कम-से-कम बंबईवासी कभी नहीं भूलेंगे।

—बंबई ब्यूरो

साक्षात्कार/ **शिशिर बजाज,** अध्यक्ष, आयुर्वेद सेवाश्रम तथा डेक्कन सेवाश्रम फार्मेसी लिमिटेड

गुणवत्ता की सर्वश्रेष्ठता

५८ वर्ष पूर्व १९२९ में झीलों की नगरी उदयपुर (राजस्थान) में सुप्रसिद्ध वैद्य (स्व०) अमृतलाल तथा १९४१ में दो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्यों पं० पंचानन गुणे शास्त्री एवं वैद्य दिवेकर ने निजाम नगरी हैदराबाद में आयुर्वेद के विकास एवं जन कल्याण के निमित्त दो अलग-अलग आयुर्वेदाश्रमों की स्थापना की, ताकि वहां विशुद्ध जड़ी-बूटियों से प्रसाधन एवं औषधियां तैयार कर विभिन्न रोगों के निदान का हल ढूंढ़ सकें। लेकिन सीमित साधनों, एलोपैथी दवाओं के बढ़ते दबाव एवं मुकाबले के सामने उदयपुर व हैदराबाद के इन दोनों आयुर्वेद सेवाश्रमों की माली स्थिति जब काफी कमजोर होने लगी, तो प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी श्री कमलनयन बजाज ने इन्हें अपने संरक्षण में लेकर उन्हें जीवनदान प्रदान किया। ये दोनों कंपनियां हैं—आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड, उदयपुर तथा डेक्कन आयुर्वेदाश्रम फार्मेसी लिमिटेड, सैदाबाद—हैदराबाद।

श्री कमलनयन बजाज ने १९५३ में आयुर्वेद सेवाश्रम का अधिग्रहण कर इसे बजाज ग्रुप की एक यूनिट बना दिया। इसमें पूंजी निवेश कर इसे कपंनी का रूप प्रदान किया। फिर ७ वर्ष बाद १९६० में प्रायवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। दूसरे वर्ष, अक्तूबर १९६१ में वाराणसी में आयुर्वेद सेवाश्रम की शाखा के अलावा उत्पादन यूनिट भी खोली गयी। उदयपुर तथा वाराणसी—दोनों संस्थानों में आधुनिकतम तकनीक एवं अत्याधुनिक स्वचालित संयंत्र स्थापित किये गये, ताकि उत्पादन के पूर्व कच्चे माल की तथा बाद में निर्मित उत्पाद की कड़ी जांच कर, उसकी गुणवत्ता को उत्कृष्ट बनाया जा सके।

उदयपुर एवं वाराणसी के दोनों संस्थानों में निर्मित केश-तैल (ब्राह्मी आंवला केश तेल, चमेली केश तेल तथा केश कल्प), दंतमंजन (लाल दंतमंजन एवं काला दंतमंजन) एवं स्पेशल च्यवनप्राश ने लिमिटेड कंपनी बनने के बाद आयुर्वेद पद्धति से बननेवाले प्रसाधनों की दुनिया में अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण काफी लोकप्रियता हासिल की—विशेषकर ब्राह्मी आंवला केश तेल, च्यवनप्राश तथा दंतमंजनों ने।

आयुर्वेद सेवाश्रम की ही तरह डेक्कन आयुर्वेदाश्रम फार्मेसी लि० को श्री बजाज ग्रुप ने १९४७ में अधिग्रहण कर, वहां पर आयुर्वैदिक दवाओं के निर्माण, पैकेजिंग के लिए जहां आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था की, वहीं अत्याधुनिक तकनीक एवं साधनों से युक्त रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट (आर०ऐंड डी०) प्रयोगशाला (अन्ना दुराई) की भी स्थापना की। यहां निर्मित होनेवाली ८० आयुर्वैदिक औषधियों में २० दवाएं उपयोगिता एवं लोकप्रियता की दृष्टि से सर्वोपरि मानी जाती हैं। 'कम किंतु श्रेष्ठ उत्पाद' के सिद्धांत को माननेवाले दोनों आयुर्वेद संस्थानों के अध्यक्ष श्री शिशिर बजाज, बजाज ग्रुप की दो बड़ी यूनिटों—हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड (गोला गोकरण नाथ, लखीमपुर खीरी, उ०प्र०) तथा उदयपुर सीमेंट—के संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं तथा श्री कमलनयन बजाज के कनिष्ठ पुत्र हैं।

पूना के प्रख्यात फर्गुसन कालेज में अर्थशास्त्र में शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिशिर बजाज पूना स्थित बजाज आटो लि० एवं बजाज इलेक्ट्रिकल्स लि० में विभिन्न विभागों में काम करने के बाद, उच्च शिक्षा के लिए १९७२ में यूरोप गये। १९७४ में न्यूयार्क विश्वविद्यालय से एम०बी०ए० की डिग्री तथा वित्त प्रबंध में विशेषता हासिल कर भारत लौट आये और हिंदुस्तान शुगर मिल्स तथा बजाज की दूसरी यूनिटों में विभिन्न उच्च पदों पर काम किया। १९८२ में दोनों आयुर्वेद सेवाश्रमों के अध्यक्ष तथा १९८५ में हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड तथा उदयपुर सीमेंट वर्क्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किये गये।

प्रस्तुत हैं, शिशिर बजाज से बातचीत के अंश :

प्रश्न : आपने बजाज ग्रुप की दूसरी बड़ी यूनिटों पर जितना ध्यान दिया, उतना आयुर्वैदिक यूनिट पर नहीं।

बजाज : एक हद तक यह बात ठीक है। पिछले पांच वर्षों से ही बजाज परिवार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है।

प्रश्न : क्या इसलिए कि यह यूनिट 'सिक' थी, व्यावसायिक रूप से फायदेमंद नहीं थी?

बजाज : नहीं, यह यूनिट कभी घाटे में नहीं रही। यह बात और है कि यह हमारी बजाज ग्रुप की दूसरी बड़ी यूनिटों जैसी 'प्राफिट अर्निंग' कंपनी नहीं थी। यह बजाज ग्रुप की एक छोटी यूनिट थी। उस समय बजाज परिवार का मुख्य ध्यान बड़ी परियोजनाओं पर था, इसीलिए कोई विशेष ध्यान इन दोनों संस्थाओं की दैनंदिन कार्य पद्धति पर नहीं दिया जा सका और बजाज यूनिट होने के नाते जिस तेजी से इनका विकास होना चाहिए था, नहीं हो सका (कुछ रुक कर) दरअसल हमने इसे तब भी और अब भी सिर्फ रुपए कमाने का साधन नहीं माना।

प्रश्न : तब तो जरूर इसे आपने समाज सेवा के रूप में लिया होगा?

बजाज : नहीं। इसे समाज सेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे जनकल्याण की भावना जरूर थी। हां, मैं आयुर्वेद को सांस्कृतिक धरोहर मानता हूं। यह विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। हमारे पुराणों-वेदों में आयुर्वेद की श्रेष्ठता के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। प्राचीनकाल में प्रख्यात आयुर्वेदाचार्यों ने जो-जो दवाएं ईजाद कीं, आज भी वे अपने मूल रूप में न केवल लोकप्रिय हैं, बल्कि रामबाण औषधि के रूप में आज भी स्वीकार की जाती हैं। मेरे पिता जी (स्व०) श्री कमल नयनजी बजाज ने जब आयुर्वेद सेवाश्रम तथा डेक्कन आयुर्वेदाश्रम फार्मेसी को अपने हाथ में लिया, तो उनका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद का घर-घर प्रसार करना था। इसके पीछे गांधीवादी दर्शन भी था। वे चाहते थे कि आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग हर कोई करे।

प्रश्न : ३४ वर्ष पहले १९५३-५४ में जब बजाज ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया, तो इसकी माली हालत काफी कमजोर थी, आप लोगों ने कैसे लाभ देने वाली कंपनी के रूप में बदला?

बजाज : हमने जब इसे लिया, तो एक छोटी इकाई के रूप में ही इसका विकास किया। अर्द्धस्वचालित यंत्र लगवाये तथा उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया, लिहाजा छोटे स्तर पर ही सही, यहां निर्मित उत्पादों ने काफी लोकप्रियता एवं उपभोक्ताओं का विश्वास अर्जित करने में सफलता प्राप्त की।

प्रश्न : उस समय इसकी शेयर कैपिटल क्या थी?

बजाज : लगभग एक लाख रु०।

प्रश्न : और अब?

बजाज : लगभग १.३० करोड़ रुपए—रिजर्व फंड सहित।

प्रश्न : जब आपने इसका अधिग्रहण किया उस समय के टर्न ओवर में एवं आज के टर्न ओवर में क्या फर्क आया?

बजाज : जमीन आसमान का। जब हमने इसे लिया, तब इसका टर्न ओवर साढ़े सात लाख था। अब १०.२५ करोड़ रु० है।

प्रश्न : यह राशि आपके प्रतियोगी संस्थानों—वैद्यनाथ प्रा०लि०, डाबर एवं झंडू के मुकाबले बहुत कम हैं। वैद्यनाथ के दावे के अनुसार उनके लगभग ७०० आयुर्वेदिक उत्पाद हैं।

बजाज : हां। (कुछ रुक कर) देखिए, मैं प्रतियोगी संस्थानों के साथ अपने मुकाबले की चर्चा यहां नहीं करना चाहता। उनकी अपने उत्पादों के बारे में अपनी नीतियां हैं और हमारी अपनी। जैसा कि मैंने पहले कहा हमने इसके व्यवसायीकरण या उद्योगीकरण की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दिया, जैसा बड़ी इकाइयों (बजाज आटो, इलेक्ट्रिकल्स, आदि) की तरफ दिया। पिछले चार-पांच वर्षों से हमने इस पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन अपनी पुरानी नीति—उत्पाद की गुणवत्ता की नीति को बरकरार रखा। अंधाधुंध नये-नये उत्पादों की भीड़ बढ़ाने के बजाय वर्तमान उत्पादों की गुणवत्ता को और भी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया।

प्रश्न : लोकप्रियता, मार्केटिंग एवं उत्पादन (प्रोडक्शन) की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा उत्पाद क्या है?

बजाज : ब्राह्मी आंवला तेल। हमारे दूसरे उत्पादों के मुकाबले इसका उत्पादन ७५ प्र०श० है। इसके बाद च्यवनप्राश, लाल एवं काला दंतमंजन तथा चमेली केश तेल है।

प्रश्न : आम आदमी की आयुर्वेद से बनी चीजों पर आस्था बहुत कम है। आप क्या सोचते हैं?

बजाज : आयुर्वेद से बनी चीजों पर जितनी आस्था होनी चाहिए, उतनी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आनेवाले दिनों में लोगों की आस्था न केवल बढ़ेगी, बल्कि आयुर्वैदिक उत्पादों का भविष्य भी काफी सुनहला होगा। लोग अब जड़ी-बूटी से बनी दवाओं तथा प्रसाधनों का उपयोग करने लगे हैं।

प्रश्न : सरकार ने आयुर्वेद के विकास के लिए एक्साइज ड्यूटी में काफी राहत प्रदान की है, फिर भी आयुर्वेद का सही ढंग से विकास क्यों नहीं हो पा रहा है?

बजाज : हां, सरकार ने कुछ राहत जरूर प्रदान की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसे तेल पर २५ प्र०श० एक्साइज ड्यूटी के बजाय सिर्फ ५ प्र०श० या बिलकुल नहीं होनी चाहिए, विशेषकर लोकल मार्केट में तो कतई नहीं होनी चाहिए। इधर सूखे के कारण तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सरकार को तुरंत तेलों का आयात कर उसे मार्केट में मुहैया कराना चाहिए।

ब्राह्मी आँवला केश तेल
BRAHMI AMLA HAIR OIL
A bajaj PRODUCT
AYURVED SEVASHRAM LTD.
सेवाश्रम उत्पादन उदयपुर

मख़मल की चादर की तरह,
आयुर्वेद सेवाश्रम के
ब्राह्मी आँवला केश तेल से
महक उठे फूलों की तरह।

सेवाश्रम

bajaj group

बालों के लिए एक नया रूप, एक नया रंग
कुदरत के गुणों के संग !

ब्राह्मी आँवला केश तेल

आयुर्वेद सेवाश्रम लि.,
उदयपुर, वाराणसी,
हैदराबाद

रजिस्टर्ड ऑफिस :
बजाज भवन,
बम्बई-४०० ०२१

आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड

श्री शिशिर बजाज
चेयरमेन, आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड

आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड पिछले ५५ वर्षों से भी अधिक समय से विशुद्ध आयुर्वेदिक प्रसाधनों का निर्माण कर समाज की सेवा कर रहा है। इसकी स्थापना सन् १९२९ में हुई थी। इतिहास प्रसिद्ध तथा राजस्थान की सौन्दर्य-स्थली, झीलों की नगरी उदयपुर में स्व. वैद्य अमृतलालजी के प्रयत्नों से यह संस्था स्थापित की गई थी। प्रारम्भ में १० से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण यहाँ शुरू किया गया। इनके अलावा आयुर्वेदिक पद्धति पर ब्राह्मी आँवला केश तेल तथा काला दन्त मंजन का भी निर्माण शुरू किया गया।

इस संस्था का कार्य उत्पादनों की गुणवत्ता के आधार पर कुछ वर्षों में ही फैलने लगा। किन्तु पूंजी व व्यापारिक दृष्टिकोण के अभाव में कठिनाइयाँ आने लगीं ऐसे समय में राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया के सत्प्रयासों द्वारा यह संस्था सन् १९५३ में बजाज परिवार के संरक्षण में आयी। तदुपरान्त बजाज परिवार ने इसे कंपनी का स्वरूप प्रदान कर इसमें पूंजी निवेश की तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन द्वारा पूर्ण सहयोग दिया। गांधीवादी दर्शन के नकशे कदम पर चलते हुये स्व. श्री कमलनयन बजाज द्वारा सिंचित एवं बजाज परिवार के अन्य सदस्यगणों तथा कुशल व्यवस्थापकों की देख-रेख में आज यह पौधा अपनी परिपक्वता की दहलीज़ पर खड़ा हुआ है। इस संस्था को बजाज परिवार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात् सेवाश्रम की कहानी "प्रगति व सफ़लता" की कहानी है।

सन् १ ६० में सेवाश्रम को प्राइवेट लिमिटेड का स्वरूप दिया गया। इस बीच इसके उत्पादन पूरे भारत में लोकप्रिय होते गये।

सेवाश्रम की बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण अक्तूबर १९६१ में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में एक शाखा खोली गई। आँवला की उपलब्धि के लिये तो वाराणसी प्रसिद्ध है ही, साथ ही पूर्व-भारत में वितरकों तथा विक्रेताओं की सुविधा की दृष्टि से भी यह स्थान उपयुक्त समझा गया। बिक्री केन्द्र के अलावा वाराणसी में एक निर्माणशाला की भी स्थापना की गई।

आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड, उदयपुर-- फैक्ट्री व कार्यालय

UDAIPUR
आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड

आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड का प्रारंभिक काल संघर्षमय रहा। परन्तु गत वर्षों में सेवाश्रम उत्पादनों की बिक्री में जो प्रगति हुई वह काफ़ी उत्साह-वर्द्धक है। कंपनी को यह श्रेय संचालक मण्डल व प्रबन्धकों की दूरदर्शिता, कर्मचारियों की कार्य-तत्परता एवं विक्रेताओं व वितरकों के स्नेहपूर्ण सहयोग के कारण मिला है।

आटोमैटिक मशीन द्वारा च्यवनप्राश की पैकिंग

शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण सेवाश्रम का व्यवसाय ही नहीं अपितु लक्ष्य भी है।

वर्तमान में विगत छः वर्षों से उत्साही युवा एवं दूरदर्शी व्यक्तित्त्व के धनी स्व. श्री कमलनयन बजाज के कनिष्ठ पुत्र, श्री शिशिर बजाज, संचालक मण्डल के चेयरमेन हैं। आपके कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप

आधुनिक स्वाचालित मशीनों द्वारा 'ब्राह्मी आँवला केश तेल'

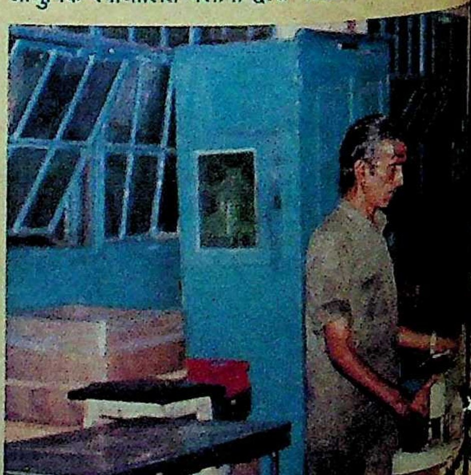

सेवाश्रम में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई है। अब समस्त सेमी-आटोमेटिक मशीनों का स्थान आटोमेटिक मशीनों ने ले लिया है जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता के साथ-साथ उत्पादनों की उत्कृष्टता में भी वृद्धि हुई है। आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया सतत जारी है।

श्री शिशिर बजाज सेवाश्रम के कार्य-कलापों में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। यह आपकी सूझ-बूझ और दूर-दर्शिता का प्रमाण है कि इन छ. वर्षों में सेवाश्रम की बिक्री लगभग दुगुनी हो गई है।

इसका मुख्य कार्यालय उदयपुर में है तथा शाखायें वाराणसी और हैदराबाद में भी हैं। देश भर में अनेक विक्रय डिपों द्वारा वितरण प्रणाली सुव्यस्थित ढंग से संचालित की जा रही हैं।

कंपनी का प्रमुख उत्पादनं ब्राह्मी आँवला केश तेल उचित मूल्यों पर देश की सुरक्षा सेनाओं को सहज उनके डिपों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

आज आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड निम्न वस्तुओं का निर्माण कर रहा है :

१. ब्राह्मी आँवला केश तेल २. चमेली केश तेल
३. स्पेशल च्यवनप्राश ४. केशकल्प
५. लाल दंतमंजन ६. काला दंतमंजन

ब्राह्मी आँवला केश तेल :-

आयुर्वेदिक पद्धति पर बनाये जाने वाले इस केश तेल में ब्राह्मी एवं आँवला का सत्व मिलाया जाता है। इस ब्राह्मी आँवला केश तेल में भीनी-भीनी खुशबू है। इसके उपयोग से बालों को मुलायम, काले, घने एवं सुन्दर बनाये रखने में सहायता मिलती है। ब्राह्मी एवं आँवला के इस मिलन से यह तेल दिमाग को संतुलित, शांति प्रदान करता है एवं उसे तरो-ताज़ा बनाये रखने में मदद करता है।

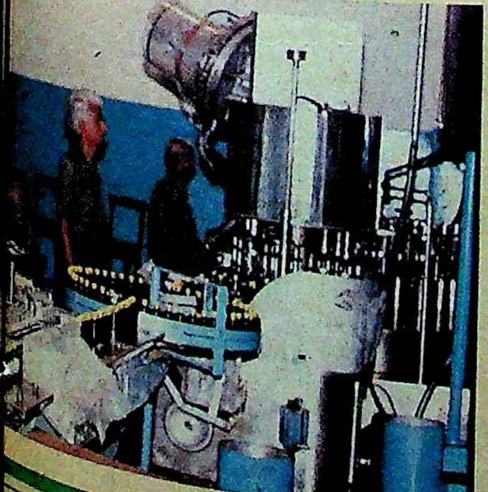

आधुनिक उपकरणों युक्त प्रयोगशाला में उत्पादनों की जाँच-परख

अत्यधिक तनाव के इस युग में इस तेल के उपयोग से मानसिक तनाव में कमी आती है। प्रत्येक वर्ग(स्त्री तथा पुरुष) के लिये यह तेल समान रूप से उपयोगी है।

चमेली केश तेल :

प्राकृतिक चमेली के फूलों की महकवाला यह एक अनोखा तेल है जो प्राचीन समय से सभी मांगलिक अवसरों पर प्रयोग में आता है।

स्पेशल च्यवनप्राश :

कंपनी ने अपने सुयोग्य प्रबन्धकों के निर्देशन में विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पर च्यवनप्राश का निर्माण लगभग दो वर्षों से प्रारम्भ किया है। इसके निर्माण हेतु आधुनिकतम मशीनों का उपयोग किया जाता है तथा इसमें आँवला एवं अष्टवर्ग, अभ्रक भस्म, शहद, चाँदी की वर्क के अतिरिक्त अनेक जड़ी-बूटियाँ मिलाई जाती हैं। यह च्यवनप्राश प्रत्येक उम्र के व्यक्ति –बालक, वृद्ध व महिलाओं के लिये समान रूप से उपयोगी है। आयुर्वेदिक पद्धति पर निर्मित इस च्यवनप्राश को आधुनिक आटोमेटिक मशीनों द्वारा मानव शरीर के छुये बिना इस प्रकार पैक किया जाता है कि यह जिस प्रकार शुद्ध निर्मित हुआ है वैसे का वैसा ही उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

केश कल्प :

यह उत्पादन आयुर्वेदिक पद्धति से निर्मित शिकाकाई युक्त बाल धोने का पाउडर है। इसके उपयोग से बाल स्वच्छ, मुलायम तथा काले बने रहते है। यह पूर्णत : हर्बल है इसलिए काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है।

लाल दंत मंजन :

यह मंजन ही नहीं अपितु एक औषधि है जो पायरीया तथा दन्तक्षय को रोकता है तथा दाँतों को चमकीले बनाता है।

काला दंत मंजन :

आयुर्वेद के आधार पर बनाये जाने वाले इस दंत मंजन में कई जड़ी बूटियाँ तथा रासायनिक तत्वों का समावेश इस तरह से किया जाता है कि इसके उपयोग से दाँत अत्यधिक मज़बूत, स्वच्छ व चमकीले रहते हैं। शास्त्रोक्त पद्धति पर आधारित अखिल भारत वर्ष में यह एक अनूठा दंत मजंन है। इसका रंग काला होने के बावजूद भी यह दातों को सफ़ेद व चमकीले बनाये रखता है।

उत्पादन की गुणवत्ता जाँच :

आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड के ये सभी उत्पादन आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशाला में जाँच-परख के पश्चात् निर्मित किये जाते हैं। इसमें प्रयोग होने वाले सभी पदार्थों की गुणवत्ता की कड़ी जाँच के पश्चात् ही उत्पादन योग्य स्वीकार करने पर उपयोग में लाये जाते हैं तथा इन जाँच किये पदार्थों के माध्यम से उत्पादित माल की पुनः प्रयोगशाला में जाँच की जाती है और उचित पाये जाने पर ही उपभोक्ताओं के लिये जारी किया जाता है।

अन्य प्रवृत्तियां :

सेवाश्रम क्लब : सेवाश्रम की उदयपुर शाखा में सर्व प्रथम इस क्लब की स्थापना हुई। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संबंधी गतिविधियां इस क्लब के माध्यम से संचालित होती रही हैं। उदयपुर के साथ-साथ वाराणसी एवं हैदराबाद में भी क्लब की शाखायें चल रही हैं।

क्लब के सांस्कृतिक एवं भ्रमण कार्यक्रम समय-समय पर होते रहते हैं। इसके अन्तर्गत कार्यकर्ता माउन्ट आबू, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, महाबलेश्वर, माण्डवगढ़, उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेपाल, तिरुपती बालाजी इत्यादि स्थानों का भ्रमण कर चुके हैं। क्लब के अच्छे कार्यकर्ताओं को प्रति वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।

कमलनयन बजाज औषधालय : सेवाश्रम एक निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधालय प्रारम्भ से ही चला रहा है। इस औषधालय के लिए एक अलग सा भवन बना कर इस औषधालय का नाम कमलनयन बजाज औषधालय रखा गया है। यहाँ अनेकों रोगियों को प्रतिदिन निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

कम्लेश्वर महादेव मन्दिर : यह मन्दिर उदयपुर व वाराणसी दोनों ही स्थानों में स्थापित है और सेवाश्रम कार्यकर्ताओं एवं कामगारों तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिये धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाने में काफ़ी सहायक रहा है। इन मन्दिरों के द्वार आम जनता के लिए भी सदैव खुले हैं।

इस प्रकार आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड अपने प्रयासों द्वारा देश के जन-स्वास्थ्य संवर्द्धन में भारतीय परम्परा के अनुसार योगदान दे रहा है।

डेक्कन आयुर्वेदाश्रम फ़ार्मसी लिमिटेड

सैदाबाद-हैदराबाद

यह संस्था पिछले ४६ वर्षों से आयुर्वेदिक उद्योग के अनुसन्धान एवं विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण कार्य मे संलग्न है। इस संस्था की स्थापना आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य पंचानन गुणेशास्त्री तथा वैद्य दिवेकर ने एक व्यवसाय के रूप में नहीं अपितु जन कल्याण की भावना को अपने मानस में रख कर की।

टैबलेट विभाग

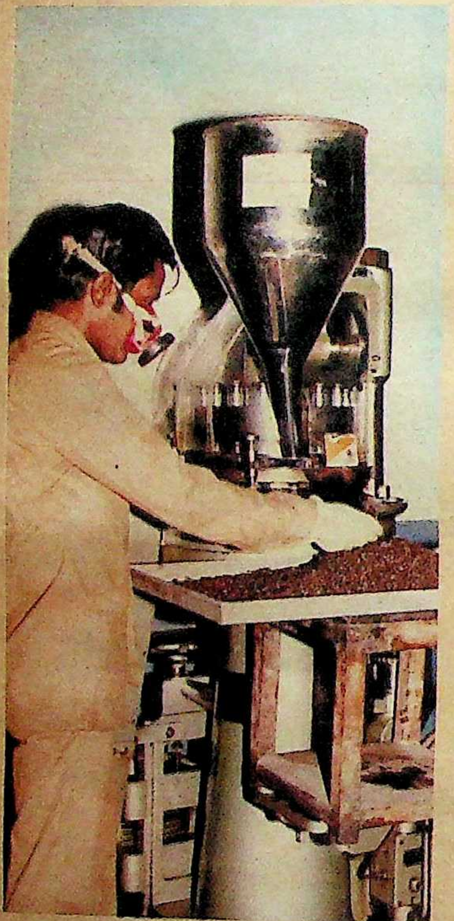

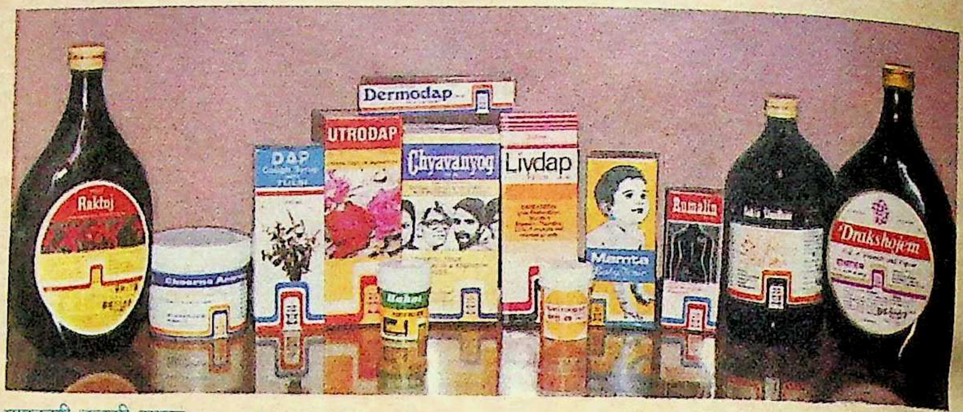

गुणकारी तुलसी समान

संस्था द्वारा निर्मित औषधियों की गुणवत्ता के आधार पर दक्षिण भारत के चिकित्सकों का संरक्षण प्राप्त हुआ है।

कम्पनी की निर्माण शाला ४६ वर्ष पूर्व एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में थी एवं स्वचलित यंत्रों के अभाव में आपेक्षित उत्पादन का अभाव रहा। शनै : शनै : इस संस्था ने अपने उत्पादन की लोकप्रियता को देखते हुए आज अपनी निर्माणशाला स्वचलित यंत्रों से सुसज्जित कर ली है।

संस्था के रूप में इस निखार का प्रारम्भ हुआ आज से ४० वर्ष पूर्व आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड की एक सहायक संस्था के रूप में। पिछले चालीस वर्षों में संस्था को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, देश के माने हुए ज्ञाता एवं विशेषज्ञों द्वारा तथा उनके अनुभव व ज्ञान का लाभ अभी भी प्राप्त हो रहा है।

संस्था के पास निर्माणशाला के अतिरिक्त आधुनिक अन्वेषण-यंत्रों से सुसज्जित प्रयोगशाला व अनुसन्धानशाला भी है। प्रयोगशाला में न सिर्फ उत्पादित उत्पादनों की परख ही होती है बल्कि उत्पादनों में उपयोग आने वाली सभी ज़डी बूटियों की गुणवत्ता की पूर्ण परीक्षा की जाती है। यही एक मुख्य कारण है किसंस्था अपने उत्पादनों की गुणवत्ता को कायम रखने में पूर्ण सफ़ल रही है।

वर्तमान में सस्था कुल ५५ विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर रही है जिनमें से बीस विशिष्ठ आयुर्वेदिक औषधियां अपनी गुणवत्ता के आधार पर देश में विभिन्न चिकित्सकों द्वारा अपनायी गई हैं।

संस्था के उत्पादन कुछ वर्षों पहले केवल दक्षिण भारत में लोकप्रिय थे। लेकिन इनकी लोकप्रियता देश के अन्य भागों में दिन प्रति दिन अब फैल रही है। उत्पादनों की विपणन व्यवस्था ६ डिपों एवं कम्पनी के प्रधान कार्यालय हैदराबाद के द्वारा संस्था के ७५० वितरकों के माध्यम से सुचारू रूप से हो रही है।

देश के जाने माने आयुर्वेद वेत्ता डा. नाडकर्णी ने अपनी पुस्तक 'इन्डियन मेटेरिया मेडिका–१९५४' के संस्करण में पृष्ठ ५०६ पर संदर्भ में कंपनी का उल्लेख किया है। इस संस्था द्वारा निर्मित औषधियों की प्रतिष्ठा का यह द्योतक है। आयुर्वेद का प्रसार तथा जन सेवा की वाहक यह संस्था बने इस ओर पूरा प्रयास किया जा रहा है।

प्रयोग शाला

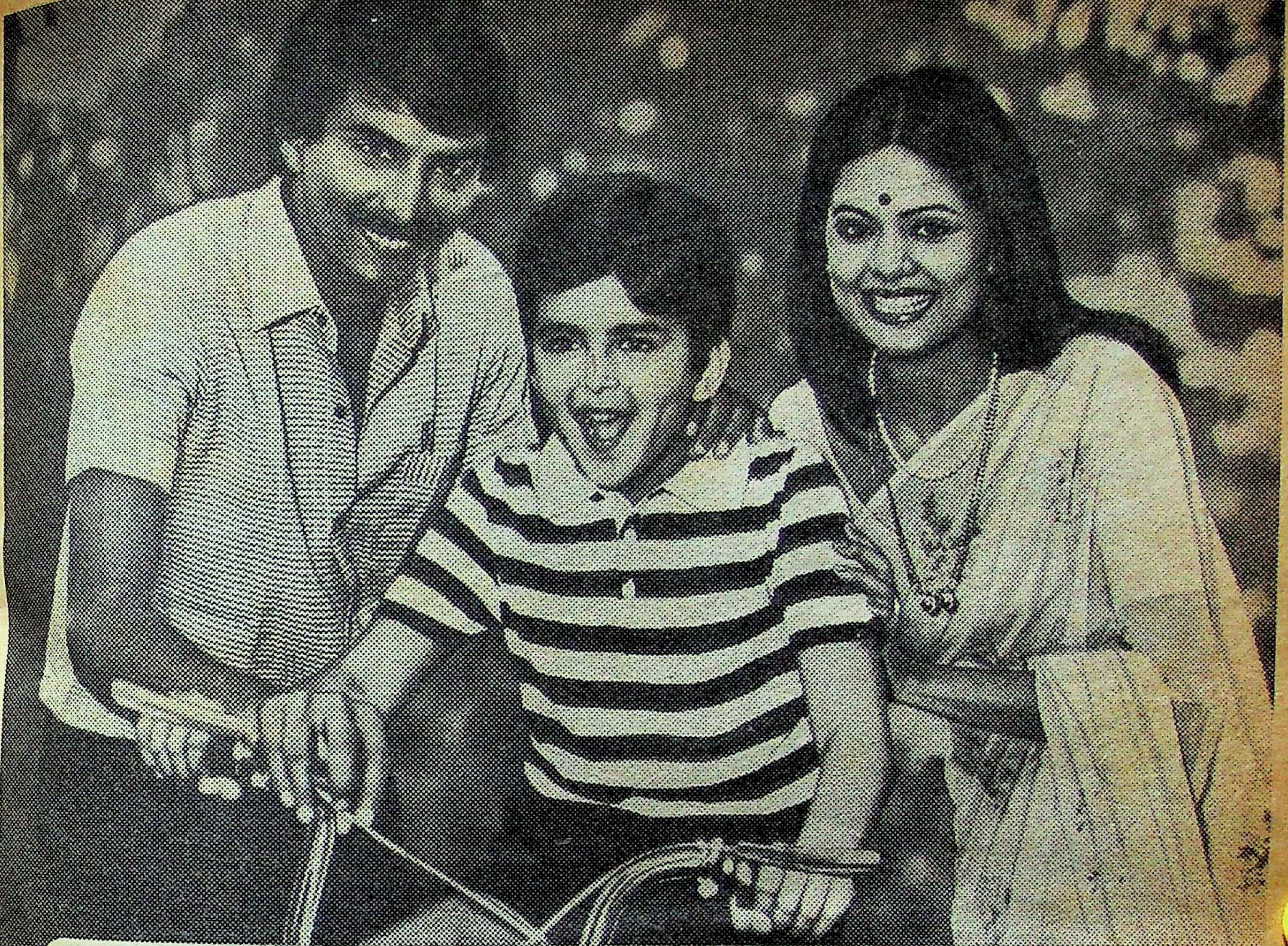

स्वास्थ्य व सुख का प्राकृतिक साधन
सेवाश्रम का स्पेशल च्यवनप्राश

सेवाश्रम का स्पेशल च्यवनप्राश, एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधी, जो आपको ताक़तवर और शक्तिशाली बनाता है। सेवाश्रम का स्पेशल च्यवनप्राश प्रकृति के उत्तम पदार्थों से तैयार किया जाता है— जैसे आँवला, अष्टवर्ग, घी, शहद, केसर, अभ्रक, भस्म, चाँदी के वर्क और अनेक जड़ी-बूटियाँ।

स्पेशल
च्यवनप्राश

bajaj group

आयुर्वेद सेवाश्रम लि., सेवाश्रम
उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद

Heros' AS 165

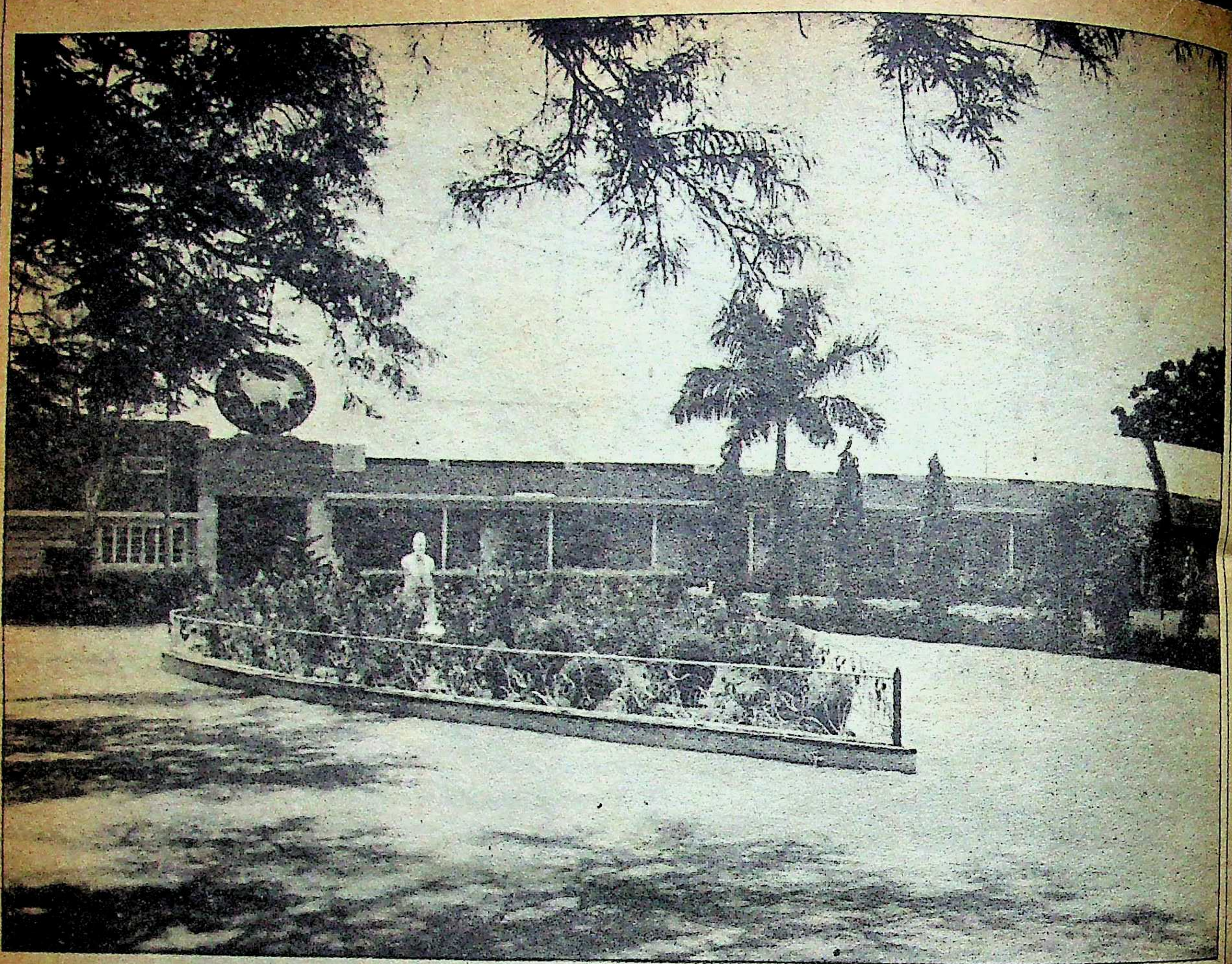

आयुर्वेद क्रांति

विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद आज प्रगति-क्रांति के उस दौर से गुजर रही है, जब सरकारी, गैर सरकारी प्रोत्साहन तथा सहायता उसे अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचा सकते हैं। वनस्पतियों–जड़ी बूटियों से बनने वाली आयुर्वेदिक औषधियों-प्रसाधनों की तरफ बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माता संस्थानों का ध्यान आकर्षित हुआ है और वे भारतीय संस्थानों की साझेदारी में विशाल स्तर पर आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन करना चाहती हैं। आयुर्वेदिक औषधियां दो हजार वर्ष की गुलामी में सिर्फ 'देसी दवाई' बनकर रह गयी थी, जिसमें न तो आधुनिक समाज की आस्था थी न ही सम्मान। प्रस्तुत है, आयुर्वेद की सर्वांगीण स्थिति पर प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य पं० सुरेश चतुर्वेदी का लेखा-जोखा:

आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा-प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से मानी गयी है। वैदिक काल में अथर्ववेद में आयुर्वेद का 'यावत्तो मूर्तमन्त भाव विशेषा लोके तावंतो देहे, यावंतो देहे तावंतो लोके' (जो मूर्तमान पंचतत्व इस संसार में है, वही हमारे शरीर में है और जो शरीर में है वही संसार में भी है) कह कर वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। इन पंचतत्वों से ही वात (वायु एवं आकाश), पित्त (अग्नि) तथा कफ (जल एवं पृथ्वी) तीनों मूल रोग पैदा होते हैं। इन तीनों रोगों के कारण हैं शरीर में सात धातुओं (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र) में होने वाले विकार। शरीर में इन पंच तत्वों में विषमता या विकार, प्रकृति के विरुद्ध अथवा शुक्र के विपरीत प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की व्याधियां पैदा करती हैं।

Hercs' AS-170

सदियाँ बीतीं, ज़माना बदला, लेकिन २000 वर्ष पूर्व के आयुर्वेदिक नुसखे नहीं बदले।

रक़्तोज–
एक रक्तवर्द्धक टॉनिक।

चूर्ण अनारदाना–
एक स्वादिष्ट पाचक।

डेप खाँसी की दवाई–
तुलसी के समान पवित्र
एवं गुणकारी डेप की
प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधि

ममता बेबी टॉनिक–
बच्चों के सर्वांगीण विकास
के लिये

च्यवनयोग–
स्पेशल च्यवनयोग कल्सीयम
तथा स्वर्ण युक्त रसायन हर
उम्र के लिये एक प्राकृतिक टॉनिक।

ममता
Mamta
Baby Tonic
Raktoj
Chyavanyog
A SPECIAL FORMULA OF CHYAVANPRASH WITH ENRICHED CALCIUM & GOLD
TONIC
& STRENGTH
DAP
Cough Syrup
with
TULSI
100 ml.
Choorna Anardana
DAP

डेक्कन आयुर्वेदाश्रम फ़ार्मसी लि.
आज की बीमारियों के लिये
कल की चिकित्सायें।

डेक्कन आयुर्वेदाश्रम
फ़ार्मसी लिमिटेड
सैदाबाद-हैदराबाद

आयुर्वेद क्रांति

आयुर्वेद का मूल उद्देश्य शरीर को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखकर स्वस्थ एवं नीरोग रखना होता है। इसीलिए आयुर्वेद को आयु का विज्ञान माना जाता है, जो लोगों के स्वास्थ्य-संरक्षण के साथ-साथ रोग-मुक्ति का उपाय भी निर्दिष्ट करता है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र को आठ अंगों में बांटा गया है—काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग (आंख, कान, नाक, गला, सिर) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, वृद्धावस्था को दूर करने के लिए रसायन चिकित्सा, सदैव युवावस्था बरकरार रखने के लिए वाजीकरण चिकित्सा।

आयुर्वेद पौराणिक एवं वैदिक काल में काफी समृद्ध रहा, हर तरह के विकार एवं रोगों की चिकित्सा-विधि तथा दवाएं आयुर्वेद पद्धति में उपलब्ध थीं जो आज भी आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में उपयोग की जाती हैं। धन्वंतरि आयुर्वेदाचार्यों के प्रपितामह माने जाते हैं और उनके चिकित्सा एवं रोग-निवान को वैद्य आज भी वज्र वाक्य मानकर पालन करते हैं।

स्वास्थ्य एवं रोग निदान के प्रथम पुरुष धन्वंतरि ने अमरत्व (दीर्घकालीन आयु), चिर-स्वास्थ्य एवं अचूक रोग-निदान के लिए जिन रामबाण औषधियों का निर्माण किया था, उनकी विधि निर्देशित की, ये सभी जड़ी-बूटियों एवं रसायनों से बनायी जाती थीं। उनके बाद हर काल में उन जैसे महान वैद्य अपने रामबाण इलाज एवं अचूक रोग-निदान के लिए प्रसिद्ध एवं चर्चित रहे हैं। रामायण काल में मेघनाद के हाथों घायल हो गये लक्ष्मण के इलाज के लिए सुखेन वैद्य, महाभारत काल में संजीवनी विद्या प्रदान करनेवाले शुक्राचार्य, शल्य चिकित्सा के प्रणेता सुश्रुत, बौद्धकाल में गौतम बुद्ध की चिकित्सा करनेवाले जीवक वैद्य, शल्य चिकित्सा पर प्रतिबंध लगने पर रसायन शास्त्र का प्रसार करनेवाले नागार्जुन ने आयुर्वेद प्रणाली को काफी समृद्ध बनाया। महाभारत में कृष्ण को कई स्थलों पर वैद्य के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है।

गुप्त काल में भारत पर आक्रमण के दौरान सिकंदर यहां की आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से इतना प्रभावित हुआ कि जाते समय वह आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित तमाम ग्रंथों के साथ-साथ तत्कालीन कई प्रमुख वैद्यों को भी ले गया और यूनानी भाषा में आयुर्वेद शास्त्र का अनुवाद कराया। कालांतर में इसका उपयोग यूनानी चिकित्सा प्रणाली में भी हुआ। यूनान से ही आयुर्वेद का प्रसार जर्मनी, फिर इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी हुआ। लेकिन अंग्रेजी भाषा की ही तरह एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली को समूचे विश्व में प्रसारित करने की अंग्रेजों की नीति के कारण आयुर्वेद का प्रसार-प्रचार इसके उत्स-देश भारत में ही ठप्प पड़ गया।

कनिष्क वंश के पतन के बाद भारत पर इस्लाम युग, फिर ब्रिटिश गुलामी के लंबे काल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हिंदू राजा-महाराजाओं, जमींदार-जागीरदारों, सेठ-साहूकारों एवं मंदिरों तक ही सिमट कर रह गयी। एलोपैथी के बढ़ते प्रभाव तथा उसे ब्रिटिश हुकूमत को मिलनेवाले राज्याश्रय ने आयुर्वेद को 'देसी इलाज' की संज्ञा देकर जो बहिष्कृत किया, उसका खमियाजा आयुर्वेद सहित दूसरी चिकित्सा पद्धतियों (होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा) को आज तक भुगतना पड़ रहा है। स्वतंत्रता-पूर्व तक देशी रजवाड़ों-जमींदारों के आश्रय के कारण आयुर्वेद का छोटे शहरों में, कस्बों एवं गांवों में जो वर्चस्व रहा और आयुर्वेद घरेलू इलाज, नानी-दादी का बटुआ किचन मेडिसिन बन कर रह गया।

गांवों के प्रति डाक्टरों की अरुचि ने सरकार का इस तथाकथित 'देसी इलाज' का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया, वैद्यों-हकीमों को गांवों-कस्बों में जाने में कोई परहेज नहीं था। धीरे-धीरे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में नगरों-महानगरों में पुरानी पीढ़ी के साथ-साथ नयी पीढ़ी का विश्वास भी जमा। औषधियां बनानेवाले उद्योगपतियों ने आयुर्वेद में विशेष रुचि लेनी शुरू की। विदेशों में औषधि-निर्माता बड़े प्रतिष्ठानों की आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति बढ़ती तीव्र रुचि ने भारतीय उद्यमियों को भी आयुर्वेद औषधियों के बड़े पैमाने पर निर्माण, उत्पादन तथा इसके लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं (रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज) शुरू करने के लिए आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, नगर एवं महानगरपालिका राज्य एवं केंद्र संचालित कतिपय अस्पतालों-कालेजों में भी आयुर्वेद डिग्री धारियों को नौकरियों की सुविधा मिलने लगी। दिल्ली-बंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में कामगार बीमा योजना के अंतर्गत भी निजी चिकित्सकों को कामगारों की चिकित्सा की अनुमति मिल गयी।

तीसरे दशक तक आयुर्वेद चिकित्सा के लिए रजिस्ट्रेशन या डिग्री की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव एवं औषधि ज्ञान के आधार पर वैद्यकी शुरू कर देता था। लेकिन १९३५ के आसपास ब्रिटिश सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का नियम बना दिया। इस नियम के तहत सभी चिकित्सक अपने अनुभवों एवं चिकित्सा जानकारी के आधार पर अपने प्रांतों में रजिस्ट्रेशन कराकर आर०एम०पी० (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैकिटशनर्स) का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते थे। आयुर्वेद विद्यालयों की स्थापना के बाद भी आर०एम०पी० प्रमाणपत्र जारी करने की पद्धति बरकरार रही, लेकिन विद्यालयों के स्नातकों एवं आर०एम०पी० सर्टिफिकेट प्राप्त चिकित्सों के स्तर में जो अंतर रखा जाता था, वह आज भी वर्तमान है। इसीलिए जैसे-जैसे आयुर्वेद विद्यालयों में वृद्धि होने लगी, सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन बोर्डों का गठन भी तेजी से होने लगा।

रजिस्ट्रेशन बोर्डों के अधिकार क्षेत्र सिर्फ संबंधित राज्य तक ही सीमित होने के कारण आर०एम०पी० वैद्यों को दूसरे राज्यों में जाकर प्रैक्टिस करने की सुविधा से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हाल में गठित नयी आयुर्वेद केंद्रीय परिषद ने वैद्यों की इस समस्या को दूर करने के लिए तात्कालिक कदम उठाने का निर्णय लिया।

शोध तथा शिक्षा की सुविधायें : इसी तरह आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध के बारे में कार्यक्रम स्वाधीनता के बाद ही शुरू हो सका। लेकिन कार्यक्रम नियोजकों का दृष्टिकोण, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के शोध सिद्धांतों से प्रभावित होने के कारण, कोई मौलिक रूपरेखा बनाने में सर्वथा असफल रहा। इसीलिए केंद्र सहायता से चलनेवाला युनिवर्सल हेल्थ इंस्टीट्यूट तथा बंबई में प्रांतीय स्तर पर औषधि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान प्रयास अपेक्षाकृत कम सफल रहे। इसके बावजूद जामनगर में स्थित आयुर्वेद संस्थान ने वनस्पतियों के अनुसंधान में काफी काम किया। बंबई के भू०पू० आयुर्वेद निदेशक तथा मूलचंद अस्पताल, दिल्ली के निदेशक वैद्य हरिदत्त शास्त्री तथा प्रख्यात वैद्य पं० शिव शर्मा ने अनुसंधान कार्य को गतिशील बनाने में सराहनीय योगदान प्रदान किया।

स्वाधीनता के एक वर्ष बाद १९४८ में आयुर्वेद की शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए सरकार ने पहली बार चोपड़ा समिति का गठन किया। चोपड़ा समिति ने मिश्र चिकित्सा प्रणाली शुरू करने का अनुमोदन किया। कुछ समय बाद सरकार ने पंडित समिति एवं दवे समिति नियुक्ति की। इन तीनों समितियों की अलग-अलग सिफारिशों के आधार पर गुरु परंपरा के आधार पर चली आनेवाली आयुर्वेद शिक्षा परंपरा का रूप बदला और आयुर्वेद विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कई विश्वविद्यालयों में भी आयुर्वेद विभाग खोले गये, जिन्होंने आगे चलकर फैकल्टी का रूप ले लिया। १९७७ तक ५० विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद फैकल्टियों की स्थापना हो गयी तथा आयुर्वेद विद्यालयों की संख्या १२० तक पहुंच गयी। कुछ वर्ष पहले जामनगर (गुजरात) में आयुर्वेद का एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इन विद्यालयों को राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान तथा दूसरी अन्य सहायता मिलती हैं।

मेडिकल कालेजों की ही तरह आयुर्वेद शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट (विज्ञान) की परीक्षा के बाद पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। एम०बी०बी०एस० की तरह आयुर्वेद स्नातकों को भी बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) की डिग्री प्रदान की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी कुछ प्रांतों में शुरू हुआ और परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले छात्रों को एम०डी० की उपाधि मिलती है। सभी आयुर्वेद विद्यालयों-महाविद्यालयों में, एलोपैथी के मेडिकल कालेजों की तरह, अस्पताल भी खोले गये, जहां मरीजों की जांच के लिए ओ०पी०डी० (बहिरंग) तथा आई०पी०डी० विभागों (आभ्यंतर विभाग) के साथ शैयाओं युक्त वार्डों की भी व्यवस्था की गयी।

एक सर्वेक्षण के अनुसार इन आयुर्वेद विद्यालयों में आनेवाले रोगी ऐसे लाइलाज रोगी होते थे, जिनका निदान दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के अस्पतालों-क्लीनिकों में विशेषज्ञ चिकित्सक तक नहीं कर पाये थे, लेकिन यही रोगी आयुर्वेद दवाओं से ठीक एवं स्वस्थ

जड़ी-बूटियोंवाला आपके दाँतों का रखवाला
आयुर्वेद सेवाश्रम का काला दंत मंजन

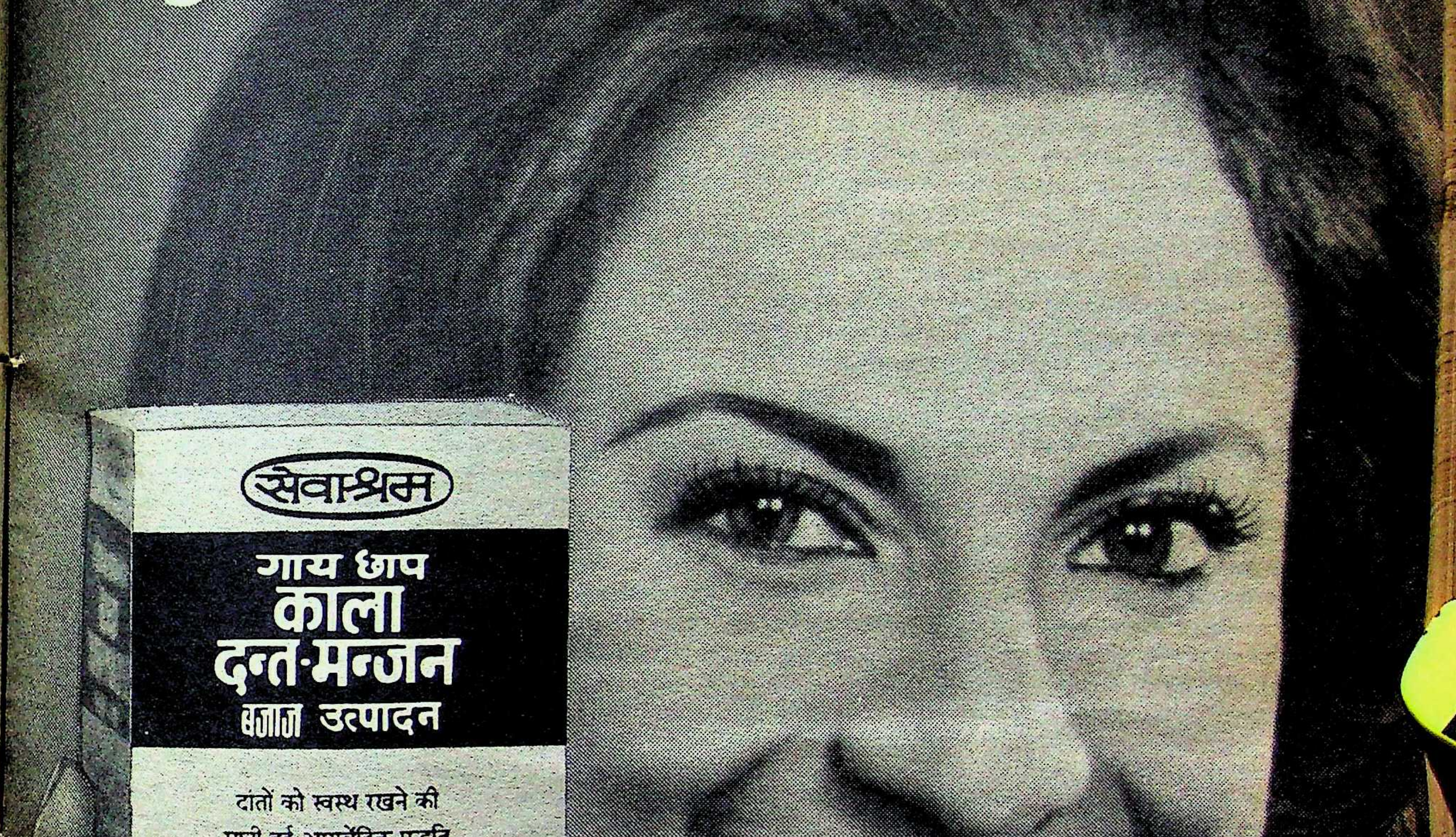
सेवाश्रम
गाय छाप
काला
दन्त-मन्जन
बजाज उत्पादन
दांतों को स्वस्थ रखने की
मानी हुई आयुर्वेदिक पद्धति
लौंग तेल, माजूफल, पोदीनासत, फिटकरी
कपूर, नीलगिरी तैल, अजवाइनसत आदि युक्त।
220 ग्राम
सेवाश्रम उत्पादन
उदयपुर
आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड
बजाज प्रतिष्ठान
स्टेशन रोड, उदयपुर-313 001
रजि० ऑ०: बजाज भवन, बंबई-400 021

तनूजा की मुस्कान आपके दाँतों की शान
सेवाश्रम का काला दंत मंजन

सेवाश्रम

आयुर्वेद सेवाश्रम लि.
उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद

bajaj group

आयुर्वेद क्रांति

हो गये। इसने जहां रोगियों में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति विश्वास पैदा किया, वहीं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होनेवाली परिचर्चाओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और स्वास्थ्य समारोहों में आयुर्वेद की दिशाएं और भी ज्यादा विस्तृत हुईं। इस तरह के आयोजनों एवं कार्यशालाओं के लिए यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारें आर्थिक सहायता एवं अनुदान देकर सहायता करती रहीं, लेकिन ४० वर्षों में जिस मात्रा में आयुर्वेद का विकास-प्रसार-प्रचार होना चाहिए था, उसका सिर्फ १० प्रतिशत ही हो सका। इसका मुख्य कारण था—सरकार की समझौतावादी नीति।

चोपड़ा समिति, पंडित समिति एवं दवे समिति और उसके बाद डा० उडुपा और फिर व्यास समिति बैठी, लेकिन इनके दृष्टिकोणों में समानता न होने के कारण इनकी रिपोर्टों पर धूल जमती गयी।

सामान्यतया विद्यालयों में मिश्र शिक्षा क्रम को ही बाहुल्य रहने के कारण भी आयुर्वेद को काफी नुकसान पहुंचा। विभिन्न राज्यों में राज्य संचालित या राज्य मान्यताप्राप्त आयुर्वेद परीक्षाओं के लिए गठित बोर्डों में भी मिश्रित शिक्षाक्रम को ही रखा गया। कई राज्य सरकारों ने जहां मेडिकल कालेजों को अधिकाधिक निजी स्तर पर खोलने की अनुमति देकर कैपिटेशन फीस की गलत परंपरा की शुरुआत की, वहीं आयुर्वेद पाठ्यक्रम को आंशिक मान्यता दी। इस मिश्रित या अति मिश्रित शिक्षा पाठ्यक्रम का ही प्रतिफल था कि बहुत से आयुर्वेद विद्यालयों में आधुनिक एनाटामी, फिजियोलाजी, सर्जरी, गायगाकोलाजी, व्यवहार आयुर्वेद, जुरिसप्रूडेंस एवं विषतंत्र, हाइजीन, तथा वर्तमान वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी की सिर्फ आंशिक व्यवस्था ही हो सकी, जबकि दूसरे मेडिकल कालेजों की तरह इनकी स्वतंत्र व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

उचित माहौल नहीं बना : आयुर्वेद की डिग्री लेनेवाले स्नातकों में इसीलिए कुंठा भी जाग्रत हुई। आयुर्वेद चिकित्सा, जो पहले वंश परंपरा एवं गुरुकुल परंपरा से बंधी हुई थी, आयुर्वेद विद्यालयों-महाविद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप खुले वातावरण में आयी और हर वर्ग के छात्रों ने इसे अपने कैरियर के रूप में अपनाना शुरू किया। लेकिन वैद्यों को जो पहले सम्मान मिलता था, वह इन युवा चिकित्सकों को एलोपैथ डाक्टरों के मुकाबले कतई नहीं मिला, न सम्मान न आर्थिक लाभ और न ही सुविधाएं। और तो और परिवार नियोजन कार्यक्रम में आयुर्वेद दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर हो सकती थी, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं किया गया। मैंने जब संबद्ध उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात की, तो उन्होंने दबी जबान से कहकर बात टाल दी कि "यह तो केंद्रीय नीति है, और केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौंपे गये उपायों का ही पालन करता है।"

इसी तरह सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं मेडिकल उच्च शिक्षा (एलोपैथी) के लिए भारत से लोगों को विदेश भेजा जाता रहा तथा वहां से विद्वानों, कलाकारों एवं छात्रों को भारत आमंत्रित किया जाता रहा, लेकिन आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कोई विशेष कारगर कदम नहीं उठाया गया, वह भी यह जानने के बावजूद कि विदेशों में आयुर्वेद के प्रति न केवल आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि 'हर्बल मेड' मेडिसिन (जड़ी बूटियों से बननेवाली दवाइयां) की निर्माता संस्थाओं के साथ विश्व की प्रख्यात बहुराष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान व्यावसायिक संबंध कायम करने के लिए लालायित हैं। यूरोप की प्रख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनी प्राक्टर-ऐंड-गैबल कं० ने जिस तरह से विक्स वेपोरब बनानेवाली रिचर्डसन हिंदुस्तान के साथ साझेदारी कर जड़ी-बूटियों से दवाएं विशाल पैमाने पर तैयार करने तथा विश्व स्तर पर उनकी मार्केटिंग का काम शुरू किया है, उससे दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी आयुर्वेदिक दवाएं तथा सौंदर्य प्रसाधन निर्माता कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित करेगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन : इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने की संभावना भारत में प्रकृति प्रदत्त अनंत काल से दबी पड़ी वनस्पति संपदा के कारण भी बढ़ेगी, क्योंकि उनके अनुसंधान और विकास से न केवल सस्ती दवाएं बनकर तैयार होंगी, बल्कि चिकित्सा विज्ञान को नयी दिशा भी मिलेगी। यह आयुर्वेद का दुर्भाग्य रहा कि एक तरफ दूसरी विभिन्न संपदाओं (प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन, ऊर्जा, आदि) के उत्खनन, तलाश पर तो सरकार व्यापक पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन हजारों दिव्य औषधियों को तैयार करनेवाली वनस्पति संपदा की खोज के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। छठीं पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद के लिए ८५ करोड़ ३६ लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपने बजट में अलग से धनराशि निर्धारित की थी। आयुर्वेदिक औषधियों पर २५ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी निर्धारित की गयी, लेकिन ४० वर्षों में जो प्रगति अपेक्षित थी, वह नहीं हो सकी।

यह आयुर्वेद का सौभाग्य ही था कि जब आयुर्वेद अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत था, दवाएं बनानेवाली फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा सौंदर्य प्रसाधन तैयार करनेवाले बड़े औद्योगिक संस्थानों की नजर जड़ी-बूटियों से निर्मित होनेवाले उत्पादों पर पड़ी। बजाज उद्योग समूह, रिचर्डसन हिंदुस्तान, बलसारा आदि बड़े औद्योगिक संस्थानों ने 'बीमार' और छोटे स्तर पर आयुर्वेद उत्पाद तैयार करने वाले छोटे संस्थानों का अधिग्रहण कर उन्हें आधुनिकतम तकनीक, स्वचालित यंत्र तथा प्रयोगशालाओं से सुसज्जित कर बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन शुरू किया। उनकी रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं में वनस्पतियों पर प्रयोग एवं अलभ्य वनस्पतियों की खोज की जाने लगी। प्राक्टर ऐंड गैबल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय औद्योगिक संस्थानों से साझेदारी कर आयुर्वेद की दुनिया में क्रांति का श्रीगणेश किया। दूसरी तरफ दशकों से आयुर्वेदिक औषधियां तथा दूसरे उत्पादों का निर्माण कर रहे बैद्यनाथ, डाबर, झंडू फार्मेसी आदि संस्थानों को व्यावसायिक प्रतियोगिता का सामना करने के लिए अपनी पारंपरिक निर्माण शैली, नीति तथा पैकेजिंग-बार्टलिंग में परिवर्तन करना पड़ा। आकर्षक बोतलों-शीशियों, पैकेटों में बंद आयुर्वेदिक उत्पादों की भिन्नता तेजी से बढ़ने लगी। अपने पारंपरिक दंत मंजन के साथ-साथ ट्यूबों में टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण शुरू किया।

इसी तरह एलोपैथ दवाओं की पैकेजिंग बार्टलिंग पद्धति को आयूर्वेद औषधियों के लिए भी अपनाया जाने लगा। आयुर्वेदिक गोलियों ने टेबलेट एवं कैप्सूल का रूप धारण कर लिया। अब तो कई औषधि निर्माता संस्थानों ने बहुराष्ट्रीय औद्योगिक संस्थानों की साझेदारी में कंप्यूटराइज्ड विधि से एलोपैथ दवाओं, के समानांतर आयुर्वेदिक औषधियों, इंजेक्शनों आदि का निर्माण शुरू कर दिया है।

१९८२ में ३३४६ आयुर्वेदिक फार्मेसियों की संख्या बढ़ कर अब लगभग पांच हजार हो गयी है। इनमें ४० से अधिक राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्युटिकल संस्थान एवं प्रसाधन निर्माता हैं, जिनका टर्न ओवर २ करोड़ से ७५ करोड़ रुपए सालाना है। विक्स वेपोरब तथा दूसरे आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली रिचर्डसन हिंदुस्तान ने प्राक्टर ऐंड गैबल की साझेदारी में अपना टर्न ओवर ४५ करोड़ से बढ़ाकर १५० करोड़ रुपए कर देने का निश्चय किया है। आयुर्वेद सेवाश्रम के अध्यक्ष शिशिर बजाज बड़े स्तर पर आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण शुरू करने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। बैद्यनाथ आयुर्वेद ने अपने संस्थान में निर्मित होनेवाले आयुर्वेद उत्पादों की संख्या लगभग ७०० बतलायी है। डाबर, झंडू की कमोबेश यही स्थिति है।

सही पूछा जाये तो यह आयुर्वेद क्रांति का युग है। अगर सरकार अगले पांच या दस वर्षों के लिए २५ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दे या सिर्फ ५ प्रतिशत निर्धारित कर दे तथा दूसरी सुविधाएं एवं निर्यात नीति में राहत प्रदान करे, तो भारी संख्या में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है और प्रति वर्ष अरबों रुपए विदेश जाने से रोक सकती है। सुदूर वनों में दबी पड़ी अकूत वनस्पति की खोज कर उनका सार्थक उपयोग कर सकती है। लेकिन सवाल है, केंद्र एवं राज्य सरकारें तथा आयुर्वेदिक उत्पादक निर्माता क्या सचमुच एक नीति निर्धारक सिद्धांत पर रजामंद होने के लिए तैयार हैं।

संप्रति प्रमुख जरूरत है, फार्मेसियों पर केंद्रीय नियंत्रण, रजिस्ट्रेशन को केंद्रीय मान्यता, सभी राज्यों के आयुर्वेद विद्यालयों का एक समान पाठ्यक्रम, अनुसंधान के लिए अधिकतम प्रयोगशालाएं, एलोपैथी के स्तर पर आयुर्वेद को लाने का प्रयास, नवगठित केंद्रीय आयुर्वेद कौंसिल एवं केंद्रीय अनुसंधान समिति को आयुर्वेद के विकास के लिए स्वायत्तता प्रदान करना।

अगर केंद्र तथा राज्य सरकारें इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को सचमुच समृद्ध बनाना चाहती हैं, तो यही सही समय है। ■

ज़रा सा मुस्कराइये या फिर खिलखिलाइये
जैसी मुस्कराहट चाहिये, अपने चेहरे पे लाइये
सेवाश्रम का
आयुर्वेदिक
लाल दंत मंजन
सेवाश्रम
लाल
दन्त
मञ्जन
(आयुर्वेदिक)
आयुर्वेद सेवाश्रम लि.
शेखर सुमन की मुस्कान
आपके दाँतों की शान
सेवाश्रम का लाल दंत मंजन
सेवाश्रम
आयुर्वेद सेवाश्रम लि.
उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद
bajaj group

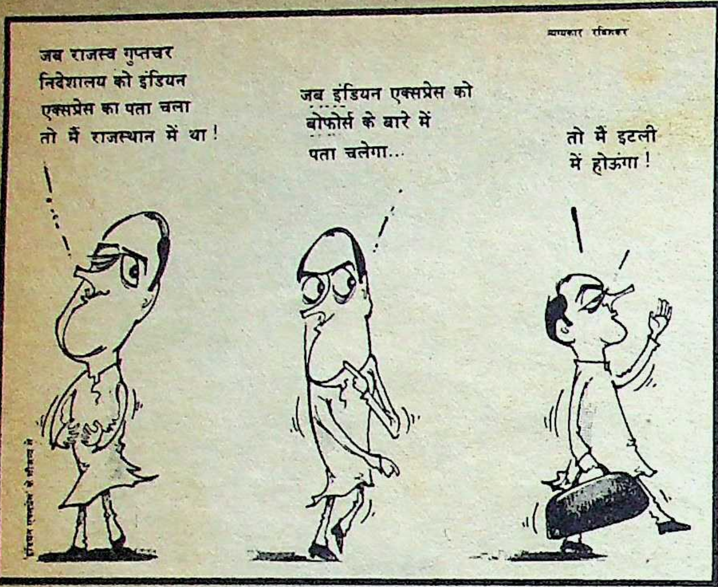
व्यंग्यकार रविशंकर
जब राजस्व गुप्तचर निदेशालय को इंडियन एक्सप्रेस का पता चला तो मैं राजस्थान में था !
जब इंडियन एक्सप्रेस को बोफोर्स के बारे में पता चलेगा...
तो मैं इटली में होऊंगा !
'इंडियन एक्सप्रेस' के सौजन्य से

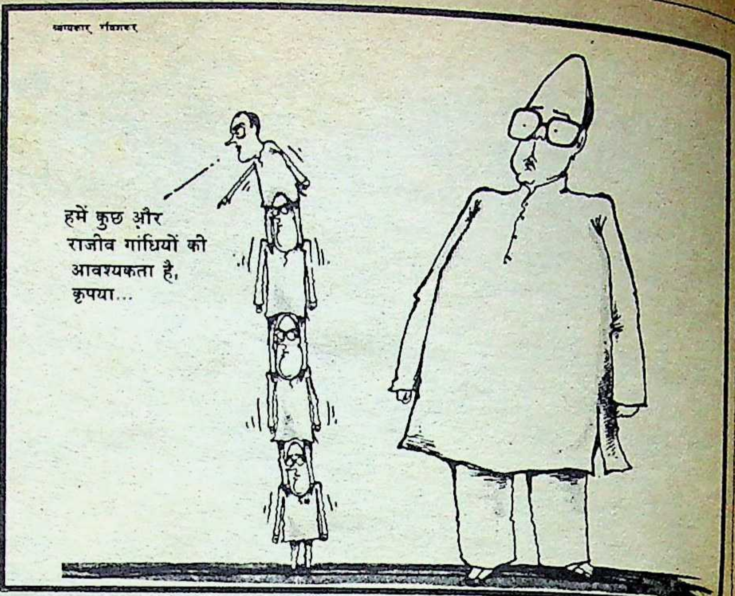
व्यंग्यकार रविशंकर
हमें कुछ और राजीव गांधियों की आवश्यकता है, कृपया...

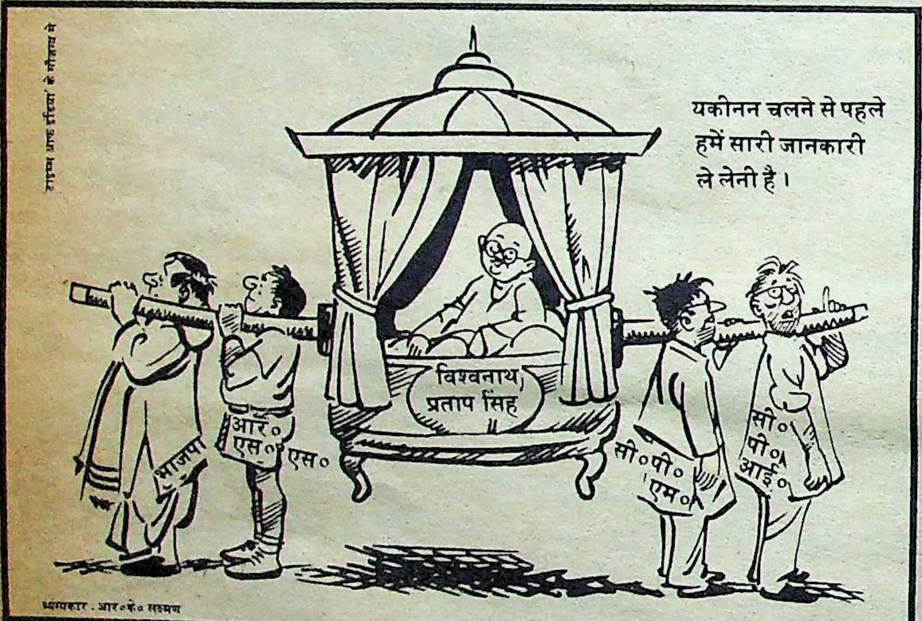
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सौजन्य से
यकीनन चलने से पहले हमें सारी जानकारी ले लेनी है ।
विश्वनाथ प्रताप सिंह
भाजपा
आर० एस० एस०
सी० पी० एम०
सी० पी० आई०
व्यंग्यकार : आर० के० लक्ष्मण

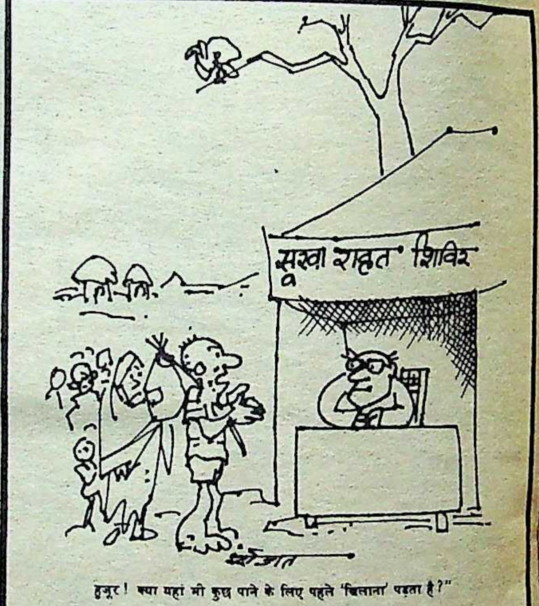

हुजूर ! क्या यहां भी कुछ पाने के लिए पहले 'खिलाना' पड़ता है ?"

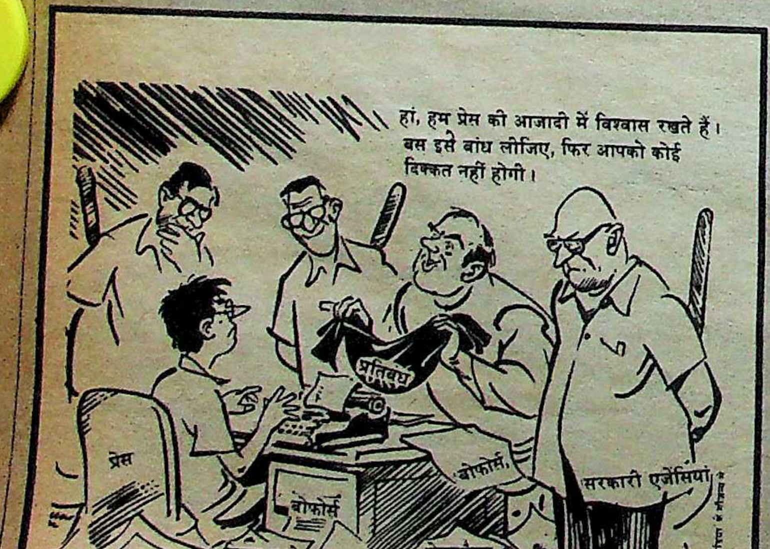
हां, हम प्रेस की आजादी में विश्वास रखते हैं । बस इसे बांध लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ।
प्रतिबंध
प्रेस
बोफोर्स
बोफोर्स
सरकारी एजेंसियां
स्विस खाते
फेयरफैक्स
पनडुब्बी सौदे
व्यंग्यकार आर० के० लक्ष्मण
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सौजन्य से

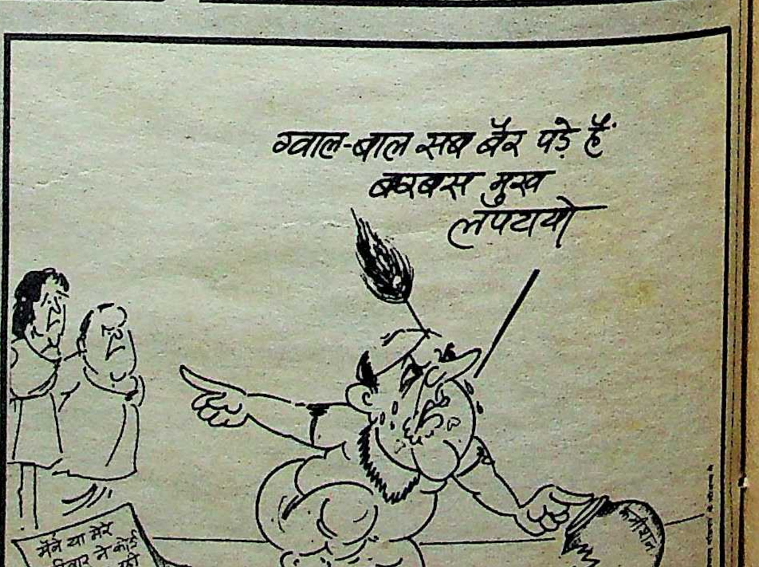
ग्वाल-बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो
मैंने या मेरे परिवार ने कोई कमीशन नहीं खाया -राजीव
कमीशन
आलोक

खतरा आसन्न : मोतीलाल वोरा छाया : गिरीश श्रीवास्तव

राजनीतिक घमासान में तेजी

यद्यपि राजीव गांधी असंतुष्टों के सामने झुक कर कांग्रेस-इ शासित राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन के बजाय असंतुष्टों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आक्रामक रणनीति पर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का भविष्य अनिश्चित माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण है, लंबी चुप्पी के बाद छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ का वोरा के खिलाफ बोलना। कमलनाथ की इस मुखरता के संदर्भ में प्रांत में कांग्रेस-इ के बदलते परिदृश्य पर **सुधीर सक्सेना** की रपट :

हालांकि, सामान्य प्रेक्षकों के लिए मंच पर सब कुछ सामान्य है, लेकिन सचाई यह है कि हाल के दिनों में नेपथ्य में घटनाक्रम में काफी तेजी आयी है। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के प्रबल समर्थकों और उनकी अंतरंग मंडली के लिए भी श्री वोरा के टिकाऊपन का दावा करना मुश्किल साबित हो रहा है। जुलाई के अंत में मुख्यमंत्री ने पंद्रह अगस्त तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही थी, लेकिन अब पंद्रह अगस्त के बाद एक महीना बीतने के बाद भी वोराजी अपनी पुरानी घिसीपिटी टीम से काम चला रहे हैं। और-तो-और, वह श्री रेवनाथ चौरे के निधन से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति भी अभी तक नहीं कर सके हैं। दिल्ली दरबार के मिजाज से वाकिफ लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए श्री वोरा को 'हरी झंडी' सिर्फ इसलिए नहीं मिली है, क्योंकि दिल्ली दरबार में अब मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की जरूरतों और उसके लाभ-हानि पर गंभीरता से विचार हो रहा है।

संकेत : मध्य प्रदेश में राजनीतिक फेरबदल का पहला स्पष्ट संकेत गत दिनों तब मिला, जब छिंदवाड़ा से निर्वाचित सांसद कमलनाथ ने जुलाई में छिंदवाड़ा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ जो आज भी प्रदेश की राजनीति में एक संतुलनकारी लाबी की अगुवाई करते हैं, ने श्री वोरा पर छिंदवाड़ा के विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा

सिंधिया से दोस्ती : अर्जुन सिह

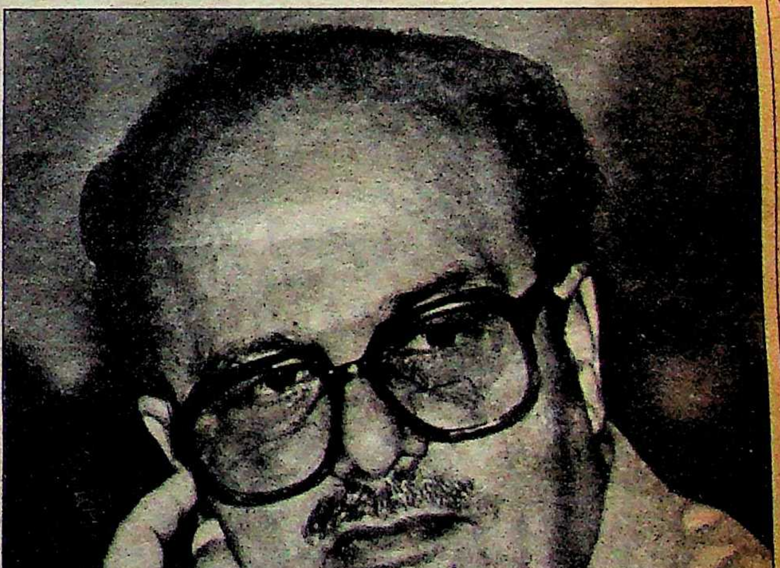

कि वोरा सरकार ने सूखे से ग्रस्त मध्य प्रदेश में राहत के मोर्चे पर देर से शुरुआत की है। कमलनाथ यदि इतना-भर कह कर मौन हो जाते, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़कर श्री वोरा पर अक्षम मुख्यमंत्री होने का आरोप भी लगा डाला। संवाददाताओं से वार्तालाप में उन्होंने अक्षमता को सहन न करने की बात भी कह डाली, जिससे इस बात को बल मिला कि दिल्ली में वोराजी की छवि एक निर्बल प्रशासक की है।

कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं, जो नाहक किसी के फटे में टांग नहीं डालते। वह सुर्खियों और विवाद में रहने के भी आदी नहीं हैं। उनके बारे मेंअरसे से यह माना जा रहा था कि वह तब तक जबान नहीं खोलेंगे और न ही प्रदेश की राजनीति में दखल देंगे, जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री का संकेत नहीं होगा। राहत कार्यों को लेकर श्री वोरा की बखिया उधेडने से यह कयास लगाया जा सकता है कि दिल्ली दरबार वोराजी को राजनीतिक कारणों से नहीं, वरन उनकी प्रशासनिक अक्षमता के कारण प्रदेश के सर्वोच्च राजनीतिक पद से हटाने के मूड में है। 'माया' संवाददाता से दूरभाष पर चर्चा में कमलनाथ ने यह बात दोहराई कि श्री वोरा उनकी नजरों में अक्षम और कमजोर प्रशासक हैं। मुख्यमंत्री के बारे में कमलनाथ के इस आकस्मिक कथन की अनुगूंज इतनी तीखी थी कि किसी ने भी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझा। हां, श्री वोरा ने यह जरूर कहा कि उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कमलनाथ की प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर श्री वोरा अपने स्वभाव के अनुसार यह कहकर कन्नी काट गये कि वह अभी सूखे की विकट स्थिति से जूझ रहे हैं और किसी राजनीतिक पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। दिलचस्प बात यह हुई कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री डा० कन्हैयालाल शर्मा को छोड़कर कोई भी अपने मुखिया के बचाव को आगे नहीं आया। डा० शर्मा ने कमलनाथ के इस कथन को तथ्यों के विपरीत बताया कि सूखा राहत कार्यों में वोरा सरकार ने देर से शुरुआत की है। डा० शर्मा का कहना था कि किसी ने भी इस क्षेत्र में इतनी जोरदार पहल नहीं की है, जितनी मोतीलाल वोरा ने।

कमलनाथ के बयान के कुछ दिनों बाद यह खबर उड़ी कि उनके विश्वासपात्र लोग श्री वोरा के खिलाफ हस्ताक्षर-अभियान चला रहे हैं। 'माया' ने इस बात की पुष्टि के लिए विधायकों से संपर्क साधा, तो पता चला कि ४० से ५० के बीच विधायकों ने मुख्यमंत्री श्री वोरा पर अक्षमता और ढीलेपन का आरोप लगाते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर कर उसे प्रधानमंत्री को भेजा है। सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार इन विधायकों, जिनमें हरिजन आदिवासी विधायकों की संख्या ज्यादा है, ने प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश में ऐसे नेतृत्व की मांग की है, जिसकी रहनुमाई में कांग्रेस-इ अगले चुनाव में सफलता पा सके।

अर्जुन गुट की सक्रियता : मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री-पद से हटाने के लिए भीतर-ही-भीतर अर्जुन गुट भी इन दिनों खासा सक्रिय है। प्रकाश चंद सेठी के पराभव और विद्याचरण शुक्ल के पार्टी से निष्कासन के बाद प्रदेश की राजनीति में अर्जुन-गुट की ताकत वैसे भी काफी बढ़ गयी है। श्री वोरा के एक समर्थक जो शासकीय उपक्रम के चेयरमैन हैं, ने 'माया' से कहा, "अब हम लोगों को यह अहसास होने लगा है कि वोराजी के लिए लड़ने या उनकी खातिर किसी से राजनीतिक दुश्मनी मोल लेने से कोई लाभ नहीं है।" विंध्य क्षेत्र के एक विधायक ने कहा, "वोराजी न तो किसी को बना सकते हैं और न ही विपत्ति पड़ने पर बचा सकते हैं। उनका साथ देना सही हो सकता है, लेकिन हाथ कुछ लगेगा नहीं।" इन बातों में दम है, इसीलिए अब अनेक लोग पूर्व मुख्यमंत्री से संबंध सुधारने के फेर में दिखायी देते हैं। अगस्त के प्रारंभ में अर्जुन सिंह जब भोपाल आये, तो उनके दो दिन के प्रवास में उनके आवास पर राजनीतिज्ञों का तांता लगा रहा। भोपाल से दिल्ली लौटने के बाद श्री सिंह ने इस आशय की खबरों का खंडन किया कि वह मध्य प्रदेश की राजनीति में पुन: लौटना चाहते हैं। आपादमस्तक कूटनीतिज्ञ श्री सिंह ने कहा कि पुन: मुख्यमंत्री बनने की उनकी निज़ी इच्छा नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो आदेश देंगे, उसका वह पालन करेंगे।

राजेंद्र प्रसाद शुक्ल

श्री शुक्ल अपने कथित भूमि-प्रेम के कारण राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में चर्चा का विषय रह चुके हैं। श्री शुक्ल अपने ही नगर में विरोध व विवाद से मुक्त नहीं हैं।

कमलनाथ

म०प्र० में राजनीतिक फेरबदल का पहला स्पष्ट संकेत तब मिला, जब सांसद कमलनाथ ने जुलाई में छिंदवाड़ा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वोरा को आड़े हाथों लिया।

श्री सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में, जैसा कि वह कहते हैं, दिलचस्पी भले ही न ले रहे हों, किंतु अपने गृह प्रदेश की राजनीति की उन्हें राई-रत्ती खबर है। प्रशासक के तौर पर श्री वोरा की निर्बलता और राजनीतिक निर्णयों में अत्यधिक विलंब से अर्जुन सिंह के गुट की ताकत में निरंतर इजाफा हो रहा है। प्रदेश की राजनीति में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री माधवराव सिंधिया और केंद्रीय संचार मंत्री अर्जुन सिंह को दो विपरीत ध्रुवों पर आसीन माना जाता है, किंतु इधर इन दिनों दिग्गज महारथी नेताओं के संबंधों में सुधार आया है। यह इस सुधार का ही सुखद परिणाम है कि श्री सिंह और श्री सिंधिया शिवपुरी के कार्यक्रमों में एक साथ दिखायी दिये। सिंह और सिंधिया में मिलाप की खबर वोरा गुट के लिए विशेष चिंतनीय इस नाते है, क्योंकि अरुण नेहरू, प्रकाश चंद सेठी और विद्याचरण शुक्ल के राजनीतिक अवसान के बाद माधवराव सिंधिया ही मोतीलाल वोरा के शुभचिंतक और रक्षक के तौर पर शेष बचे हैं। श्री वोरा के लिए यह भी चिंता का विषय हो सकता है कि अर्जुन सिंह और अ०भा० इंका के महासचिव सांसद सुरेश पचौरी के पारस्परिक संबंधों के खटास में कमी आयी है। 'माया' के सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं को एक बार फिर नजदीक लाने में श्री सिंह के विश्वासपात्र सांसद जगतपाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। श्री पचौरी व उनके उत्तराधिकारी मध्य प्रदेश युवा इंका के अध्यक्ष व सांसद सुरेंद्रसिंह ठाकुर मुख्यमंत्री श्री वोरा से इस कारण खिन्न हैं कि वोरा के राजकाल में युवा इंका को वैसा महत्व व सम्मान नहीं मिल रहा है, जैसा अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में मिला करता था। श्री सिंह और श्री पचौरी में संबंध यदि वाकई सुधरते हैं, तो अर्जुन गुट को श्री वोरा को पस्त करने और तख्त पर अपने आदमी को बिठाने में सहूलियत होगी तथा श्री पचौरी को यह लाभ हो सकता है कि अर्जुन गुट के युवा नेता, युवा इंका के अध्यक्ष पद से श्री ठाकुर को हटाकर युवा इंका हथियाने का अभियान बंद

कर दें। यह बात अब उजागर हो चुकी है कि भा०रा०छा०सं० के पूर्व अध्यक्ष और विधायक मुकेश नायक अब म०प्र० युवा इंका के अध्यक्ष बनने को लालायित और सचेष्ट हैं। यह भी खबर है कि अर्जुन सिंह के सुपुत्र अजय सिंह (राहुल), मुकेश नायक और एस०एन० सिंह जैसे अपने विश्वासपात्र लोगों को युवा इंका मे महत्वपूर्ण पद दिलाने के इच्छुक हैं। ऐसे में श्री सिंह और श्री पचौरी में मेलमिलाप युवा इंका की राजनीति के समीकरणों में दूरगामी परिवर्तन ला सकता है। सरकारी उपक्रमों के अनेक अध्यक्ष भी इन दिनों मुख्यमंत्री श्री वोरा से नाराज हैं। अर्जुन गुट के राजमणि पटेल (अध्यक्ष, सेतु निगम) ने ८ अगस्त को निगमों के अध्यक्षों की एक बैठक अपने घर पर बुलायी, जिसमें अध्यक्षों की उपेक्षा व प्रबंध संचालकों की मनमानी पर रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने का फैसला किया गया।

सुरेश पचौरी

श्री सिंह और श्री पचौरी में संबंध यदि वाकई सुधरते हैं, तो अर्जुन गुट को श्री वोरा को पस्त करने और तख्त पर अपने आदमी को बिठाने में सहूलियत होगी।

तकरार: और कुछ हो या न हो, लेकिन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और प्रदेश इंका के अध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह में ठनी हुई है। वोरा के पक्षधर बालकवि बैरागी जैसे सांसद प्रधानमंत्री के पास जाकर एकाधिक बार दिग्विजय सिंह की शिकायत कर आये हैं। मजे की बात यह है कि अपनी तुकबंदियों से अलग-अलग मौकों पर प्रधानमंत्री का मन मोहनेवाले बालकवि बैरागी स्वयं प्रदेश इंका का अध्यक्ष बनने की दौड़ में शरीक हैं। जो दो अन्य सांसद दौड़ में शामिल हैं, उनके नाम हैं—विदिशा के प्रतापभानु शर्मा और झाबुआ के दिलीप सिंह भूरिया। कुछ लोग इस सूची में होशंगाबाद के रामेश्वर नीखरा का भी नाम जोड देते हैं। मुख्यमंत्री श्री वोरा भूरिया-शर्मा-बैरागी की त्रयी में से ही किसी को इंकाध्यक्ष बनाने के फेर में बताये जाते हैं। जहां तक अर्जुन गुट की सक्रियता का प्रश्न है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि दिग्विजय सिंह इस पद पर बने रहें, लेकिन यदि दिल्ली दरबार उन्हें हर हाल में अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला कर लेता है, तो अर्जुन गुट ऐसी स्थिति में सहकारिता के बेताज बादशाह सांसद सुभाष यादव पर दांव लगायेगा।

प्रदेश इंका के अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल दिलीप सिंह भूरिया का दावा काफी सशक्त माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के संसदीय पक्ष के संयोजक श्री भूरिया के पक्ष को निर्बल करने के लिए हाल में कुछ आदिवासी विधायकों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र श्री भूरिया के खिलाफ सौंपा है। जाहिर है कि वर्तमान अध्यक्ष इस खत का राजनीतिक उपयोग करने से चूकेंगे नहीं। कुछ दिनों पूर्व भोपाल में पार्टी की बैठक में थांदला के विधायक कांतिलाल भूरिया सांसद श्री भूरिया को आड़े हाथों ले चुके हैं। दूसरी ओर दिलीप सिंह भूरिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह और उद्योग मंत्री भारत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत सिंह आदिवासी जिलों—झाबुआ और खरगोन के प्रभारी मंत्री हैं। दिलीप सिंह भूरिया का कहना है कि उनके खिलाफ खत पर आदिवासी विधायकों के हस्ताक्षर दिग्विजय सिंह और भारत सिंह ने विधायकों को भ्रमित करके लिये थे। उधर एक महामंत्री ने सांसद भूरिया के निष्कासन की ही मांग कर डाली है। कहना न होगा कि यह सब दो नेताओं के बीच जारी और अब निरंतर तेज हो रहे शीतयुद्ध का ही नतीजा है। हालांकि, दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पर श्री वोरा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके नजदीकी सूत्रों के अनुसार राजा साहब वोराजी से इसलिए खिन्न और रुष्ट हैं कि वह एक तो उनकी विरोधी राजनीतिक लाबी को हवा दे रहे हैं, दूसरे उन्होंने उनके पुराने प्रतिद्वंदी डा० भंवर सिंह पोर्ते और उनकी संस्था आदिवासी विकास परिषद को सरकारी प्रश्रय दे रखा है, जबकि परिषद के मंच से फिर से पृथक गोंडवाना की मांग उठने लगी है।

दिलीप सिंह भूरिया

दिलीप सिंह भूरिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह और उद्योग मंत्री भारत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

श्री वोरा और उनके सिपहसालार इस तथ्य से परिचित हैं कि युवा और खुशमिजाज दिग्विजय सिंह में पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता और सूझबूझ है और वह प्रधानमंत्री के नजदीक होने के नाते उनकी पसंद भी हो सकते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का प्रश्न है, विधानसभा-अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ल और पूर्व उपमुख्यमंत्री (अब केवल मंत्री) शिवभानु सोलंकी दावेदारों की पहली पांत में हैं। इनमें श्री शुक्ल अपने कथित भूमि-प्रेम के कारण राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में चर्चा का विषय रह चुके हैं। श्री शुक्ल अपने ही नगर में विरोध व विवाद से मुक्त नहीं हैं। रहे श्री सोलंकी, सो लियाजां में सिफर श्री सोलंकी की असल पूंजी यह है कि वह एक तो आदिवासी हैं, दूसरे कई सालों से मंत्री-पद पर आसीन हैं। इन दोनों के अलावा और भी कई लोग मुख्यमंत्री बनने के फेर में हैं। मंत्री बनने को तो हर इंका विधायक लालायित है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मध्य प्रदेश के बारे में शीघ्र फैसला लेने को प्रेरित कर सकते हैं। सांसद विद्याचरण शुक्ल मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करने का मन बना चुके हैं। 'विश्वनाथ प्रताप मित्र संगठन' का गठन हो चुका है और पत्रकार नागरिक मंच के चारु झा दिल्ली जाकर वी०पी० सिंह को मध्य प्रदेश के दौरे का न्योता दे आये हैं। इधर प्रदेश के विधायकों और नेताओं का दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भेंट करने का सिलसिला जारी है। ७ अगस्त को विष्णु राजौरिया, मुकेश नायक, चरण दास महन्त और अरुण तिवारी आदि विधायकों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट की। श्री राजौरिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्माण व विकास कार्यों से संबंधित शिकायतों व मांगों के करीब साढ़े चार सौ पत्रों की वे १८ फाइलें प्रधानमंत्री को सौंपीं, जिन्हें करीब तीन महीने पहले उन्होंने निराकरण के लिए श्री वोरा को सौंपा था, लेकिन उन पर इस दरम्यान कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक द्वय मुकेश नायक और अरुण तिवारी ने, बताते हैं, प्रधानमंत्री से प्रदेश में सक्षम नेतृत्व की मांग की। सौभाग्य से अगस्त-अंत की वर्षा ने सूखे की भयावहता को कम कर दिया है, अन्यथा तंत्र में खोट और प्रशासनिक शिथिलता के कारण राहत कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सरकार को अभूतपूर्व परेशानी में डाल देता। इस बारिश से पेयजल और चारे की कमी का विराट भय छोटा जरूर हुआ है, किंतु राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक दृश्यावली में परिवर्तन का आसार कई गुना बढ़ गया है। ■

छाया: आर०सी० साहू 'बिम्ब'

देश आंकड़ों के आइने में

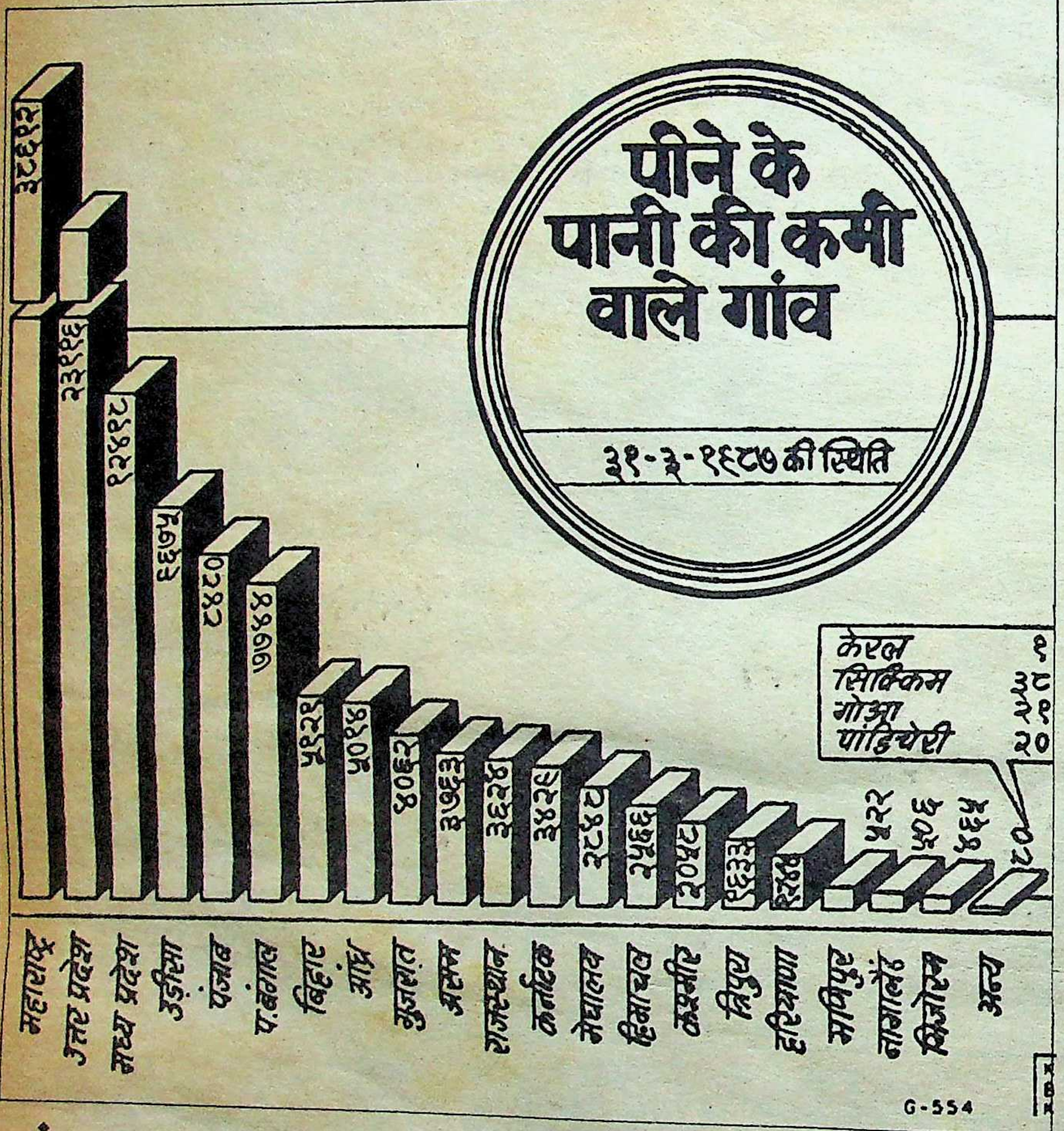

पीने के पानी की कमी वाले गांव

३१-३-१९८७ की स्थिति

संसद के प्रश्नोत्तरों और विभिन्न शोध एजेंसियों के सर्वेक्षणों से हर पखवाड़े विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकाश में आते रहते हैं जो बिना विश्लेषण के ही संबंधित विषय की पूरी कहानी कह देते हैं। प्रस्तुत हैं, पिछले पखवाड़े में प्रकाश में आये ऐसे ही कुछ आंकड़े:

पिछले तीन सालों में भारत ने विदेश व्यापार में २३८ अरब, १९ करोड़ एक लाख रुपए का घाटा उठाया है। यह घाटा १९८४-८५ में ६७ अरब २१ करोड़ एक लाख रुपए, १९८५-८६ में ९५ अरब ८६ करोड़ और १९८६-८७ में ७५ अरब, १२ करोड़ था।

देश के ७४१ रोजगार दफ्तरों में नवंबर १९८६ तक बेरोजगारों की सूची में करीब तीन करोड़ नाम दर्ज थे। १९७६ में बेरोजगारों की संख्या २६ लाख २२ हजार थी, अर्थात दस वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन करीब तीस लाख बेरोजगार रोजगार दफ्तरों में अपना नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन सरकार करीब साढ़े तीन लाख लोगों को ही प्रति वर्ष रोजगार दे पाती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीन करोड़ से अधिक तो वे बेरोजगार हैं, जिन्होंने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज ही नहीं करवाये हैं।

श्रीलंका से भारत में एक लाख, २४ हजार एक सौ ८० तमिल शरणार्थी आये हैं जो वापस जाने की प्रतीक्षा में हैं।

मेढक की टांगों के निर्यात से भारत प्रतिवर्ष सात करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारत में २७ प्रजातियों के ११६ किस्म के मेढक पाये जाते हैं, जिनमें से केवल तीन किस्म के मेढकों की टांगों का ही निर्यात किया जाता है। मेढक की टांगों को विदेशी बड़ी रुचि से खाते हैं।

पिछले तीन मासों में खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में २१.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पिछले दो वर्षों में इनकी कीमतें सौ प्रतिशत तक बढ़ गयी हैं।

१९५९ में देश में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन ७४.९ ग्राम दाल उपलब्ध थी। आज सिर्फ ५ ग्राम दाल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिस्से आती है। यह तो औसत आंकड़ा है, जबकि देश की ४० प्रतिशत आबादी को दाल तक नसीब नहीं होती।

देश के कुल ४०७ जिलों में से २६० जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। इन जिलों के करीब ५० करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित हैं।

एशिया और प्रशांत महासागर के २० मुल्कों में सबसे ज्यादा अनपढ़ अफगानिस्तान (७६.३ प्रतिशत) में हैं, दूसरे नंबर पर नेपाल (७४.४ प्रतिशत), तीसरे पर पाकिस्तान (७०.४ प्रतिशत) और चौथे पर बंगलादेश (६६.९) आता है। अनपढ़ देशों में भारत का पांचवा स्थान है, यहां ५६.९ प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले चीन में अनपढ़ों की संख्या सिर्फ तीस प्रतिशत है।

पिछले चार-पांच सालों में भारतीय रुपए में ४० प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ है।

पिछले तीन वर्षों में हुए सांप्रदायिक दंगों में ७८७ व्यक्ति मारे गये और २१ करोड़ ४२ लाख ८९ हजार रुपए की संपत्ति नष्ट हुई।

पंजाब में पिछले २२ महीनों (१ अक्तूबर, १९८५ से १ अगस्त, १९८७) में आतंकवादियों ने १११७ लोगों की हत्या की, जबकि पुलिस बल ने २२५ आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले तीन महीनों में आतंकवादियों ने ११३० वारदात कीं।

पिछले तीन वर्षों में पान के निर्यात में लगातार कमी आयी है। १९८४-१९८५ में ११० लाख रुपए, १९८५-८६ में ६१ लाख रुपए और १९८६-८७ में ५० लाख रुपए का पान निर्यात किया गया।

DART/EF/1989/HIN

उत्कृष्ट उपहार

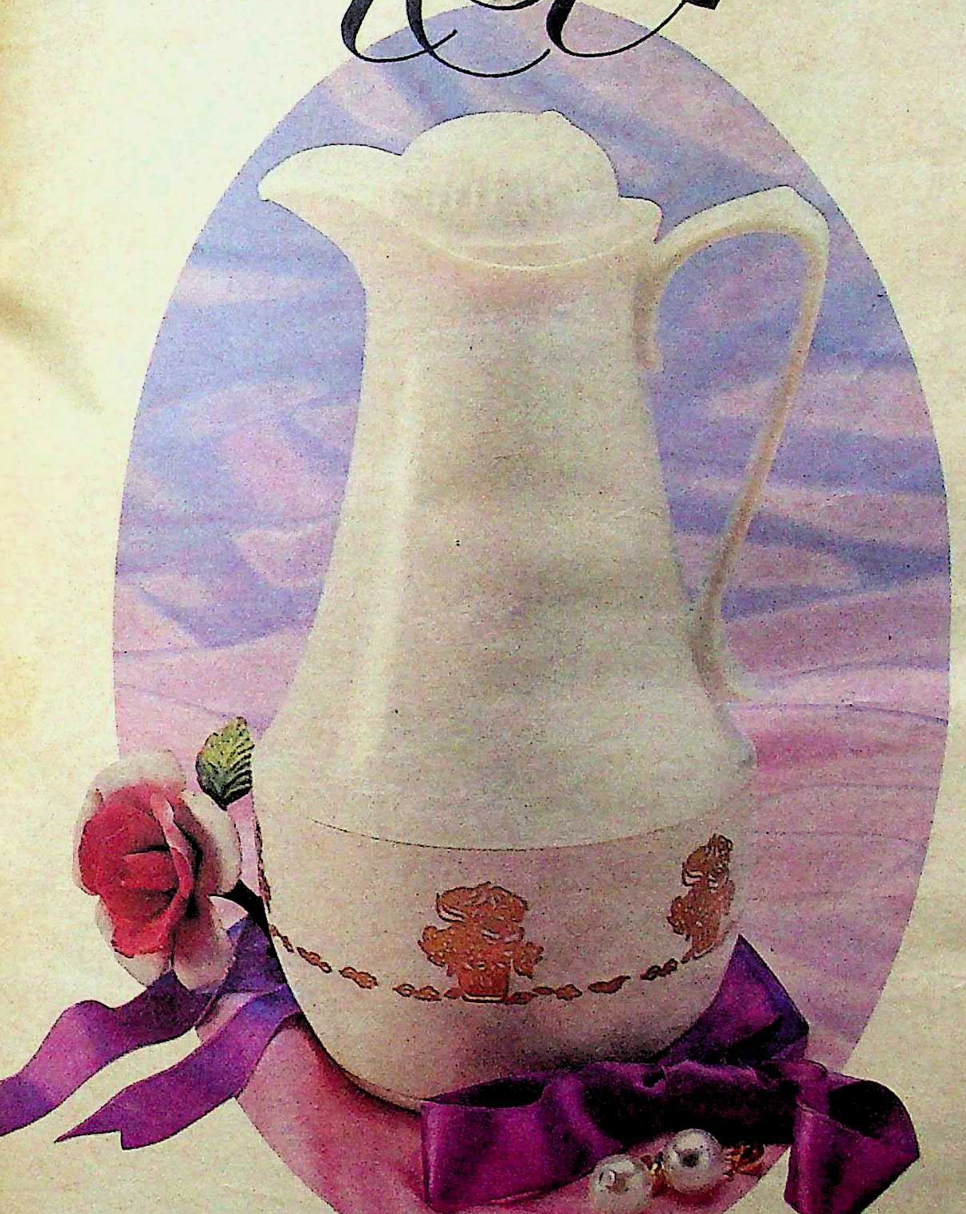

सर्वोत्तम...
केवल ईगल की ओर से !

आपका ईगल उपहार विशिष्ट श्रेणी में आता है।
उत्तम क्वालिटी, खास डिज़ाइन और आकर्षक रंग.....
तिस पर ऐसी बेजोड़ बनावट - बहुमुखी उपयोगिता।
ईगल उपहार सबसे पसंदीदा उपहार। यह एक सम्मान
है सर्वोत्तम वस्तु में आपकी रुचि का।

ईगल फ़्लास्क
प्रा. लि.

पंजीकृत कार्यालय एवं प्लांट - I
तलेगांव - ४१० ५०७, जिला - पुणे (महाराष्ट्र)
ग्राम : 'ईगल फ़्लास्क' पुणे - ४१० ५०७, फ़ोन : ३२१ — ५
टेलेक्स : ०१४५ - २९६ EGLE IN

प्लांट - II
इंडस्ट्रियल इस्टेट, गिंडी, मद्रास - ६०० ०३२
फ़ोन - ४३१०९५/४३३८७४, टेलेक्स : ०४१/७१०१ EAGL IN

कार्यवाहक कार्यालय :
बंबई, फ़ोन : ३२२०९६/९७, टेलेक्स : ०११ - ७३२९७ EGLE IN

बिक्री कार्यालय एवं डिपो :
चंडीगढ़ * दिल्ली - ३३१ ५०६६/७३१५६१ * जयपुर
* कानपूर * कलकत्ता २६७३५० * गोहाटी * रांची २२४४६ *
अहमदाबाद ३९१०२८ * इंदौर ६४३५६
* बंगलौर २२३२९९ * हैदराबाद ६७०८८ * मद्रास २४२७० *
त्रिचूर * गुंटूर * काकिनाडा * विजयवाड़ा

डाइनैट सैट

रिफ्रेशर सैट

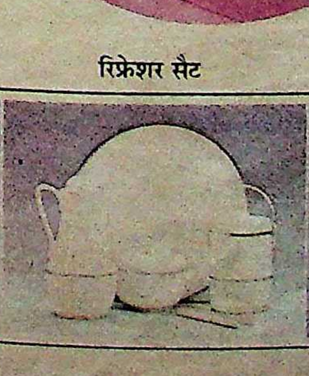

टी टाइम सैट

देखा कितने काम आए ईगल!

कारों का स्वप्न लोक : रियाद का अल नसीम कार बाजार

रियाद: कार-प्रेमियों का स्वर्ग

सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अल नसीम क्षेत्र में ही कारों का वह विश्वविख्यात बाजार स्थित है, जहां दुनिया के कोने-कोने से कारों के शौकीन सिर्फ इस हसरत से पहुंचते हैं कि वे अत्यंत सस्ती कीमत पर कोई मशहूर और कीमती कार खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकें। २ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह विशाल बाजार आयताकार है। साफ-चिकनी सड़कें हैं। रंग-बिरंगी चमचमाती खूबसूरत कारें एक कतार में धीरे-धीरे आंखों के सामने से गुजरती हुई अपने-अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी हो जाती हैं।

वहां नीलामीकर्ता के खड़े होने के लिए कंक्रीट के छोटे-छोटे मंच बने हैं। पारंपरिक अरबी वेशभूषा (घुटनों के नीचे तक पहुंचता सफेद अंगरखा और सिर पर लाल रंग का स्कार्फ नुमा कपड़ा) में नीलामीकर्ता इन मंचों पर खड़े हैं। उनके हाथों में माइक्रोफोन हैं, जिनसे वे अरबी में इन कारों की कीमतें चिल्ला-चिल्लाकर बता रहे हैं। वहां भारतीय, पाकिस्तानी, यमनी, सूडानी, मिस्री, अमरीकी आदि विभिन्न मुल्कों के लोगों की नजरें इन मनभावन कारों पर टिकी हैं। कारें इतनी खूबसूरत हैं कि यह तय कर पाना सरल नहीं है कि किसे लें और किसे न लें। ये कारें शानदार हैं, जबकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। किंग सऊद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पाल मजकट का तो कहना है, “कारों का यह बाजार अद्वितीय है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, लेकिन ऐसा नजारा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, अमरीका में भी नहीं।” रियाद के अलावा सऊदी अरब में जद्दाह और दमन में कार-नीलामी बाजार हैं। लेकिन अल नसीम क्षेत्र में स्थित कार बाजार की बात ही कुछ और है। यहां एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग पांच लाख कारों की चाभियां एक हाथ से दूसरे हाथों में चली जाती हैं।

अल नसीम के कार बाजार में जैसी चहल-पहल रहती है, उसकी तुलना किसी बाजार से नहीं की जा सकती। यहां तक कि अमरीका और इंग्लैंड में भी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता—लेकिन भारतीय बाजारों से इसकी कमोबेश तुलना की जा सकती है। वही हंसी के ठहाके, शोर-शराबा, भीड़-भाड़ और वातावरण में पेट्रोल के गंध के बीच दिखायी देती हैं दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक दूसरे से सट कर खड़ी अनगिनत रंग-बिरंगी कारें।

सौदेबाजी : कारों की बिक्री का धंधा थोड़ा टेढ़ा है। कार-विक्रेता की कोशिश रहती है कि कार को नीलामी पर चढ़ाने से पहले ही उसे कोई खरीदार मिल जाये। वह संभावित खरीदार को आकृष्ट करने के लिए अपनी कार को बाजार में चारों ओर घुमाता है। व्यक्तिगत स्तर पर कारों का सौदा करने के इच्छुक ग्राहकों की वहां कमी नहीं होती। ऐसा ग्राहक उस अरब से कहता है, ‘लिलबिया’ अर्थात क्या आप कार बेचना चाहते हैं? यदि उत्तर हुआ ‘ऐवा’ अर्थात् ‘हां’ तो फिर सौदेबाजी शुरू हो जाती है। कार धीरे-धीरे सरकती रहती है और मोल-तोल होता रहता है। यदि सौदा पट गया, तो कार ग्राहक की हो जाती है, अन्यथा वह अरब भुनभुनाते हुए कहता है, ‘या मस्सरी’ अर्थात ‘मिस्री’। (मिस्र के लोगों को अरब कंजूस मानते हैं और जिसे वे कंजूस कहना चाहते हैं, उसे वे व्यंग्यपूर्वक ‘मस्सरी’ कहते हैं।)

व्यक्तिगत बातचीत में सौदा नहीं पटता, तो कार विक्रेता के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि वह अपनी कार को नीलामी पर चढ़ा दे। अल नसीम मार्केट में पचास से अधिक नीलामीकर्ता हैं। वे दो फुट ऊंचे मंच से नीलामी शुरू करते हैं। यदि वहां कोई बोली बोलनेवाला (मुजादीन) न हुआ, तो स्वयं नीलामीकर्ता (मोहरेज) बोली बढ़ाता जाता है। अंतिम बोली खतम होने के बाव-

जूद यह जरूरी नहीं कि कार बिक ही जाये। विक्रेता को यदि अपेक्षित कीमत नहीं मिलती तो वह अपनी कार नहीं बेचता, लेकिन यदि वह अंतिम बोली से संतुष्ट हो जाता है, तो सौदा पट जाता है। इस नीलामी में कार-विक्रेता नीलामीकर्ता को ५०० सऊदी रियाल (करीब डेढ़ हजार रुपए) नीलामी की फीस के रूप में देता है।

पुरानी कारों का बाजार : कार नीलामी के साथ-साथ अल नसीम के कार बाजार में पुरानी कारों की भी बिक्री होती है। वस्तुत: नीलामी में अकसर पुरानी कारें ही अधिक बिकती हैं। अकसर मोहरेज स्वयं बोली लगाकर ऐसी कारें खरीद लेते हैं और एक हजार सऊदी रियाल (करीब तीन हजार रुपए) के लाभ पर उन्हें फिर से बेच देते हैं। वहां ऐसे भी नीलामीकर्ता और पुरानी कारों के विक्रेता हैं, जिनके शो-रूम में अकसर सौ-सौ गाड़ियां बिक्री के लिए हरदम उपलब्ध रहती हैं।

अल नसीम कार मार्केट ग्राहकों को कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में विनोद नैयर ने ६ हजार रियाल (करीब १८ हजार रुपए) में एक डाटसन कार खरीदी थी। कार के स्वामित्व के हस्तांतरण और सौदे से संबंधित कागजात तैयार कराने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। १०० रियाल (करीब तीन सौ रुपए) में सौदे के कागजात और ३०० रियाल (करीब नौ सौ रुपए) में स्वामित्व हस्तांतरण के मुकम्मल दस्तावेज विनोद नैयर को ४८ घंटों के अंदर ही मिल गये थे। इसका मतलब है कि अतिरिक्त धन खर्च करके विनोद नैयर कार के दस्तावेजों के लिए तेज धूप में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भटकने से बच गये।

विशेष सरगर्मी : अल नसीम के इस कार बाजार में सप्ताह के सातों दिन चहल-पहल रहती है, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में ही सबसे ज्यादा खरीद-फरोख्त होती है। हर गुरुवार की शाम पांच बजे से इस बाजार में विशेष सरगर्मी शुरु हो जाती है। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को वहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। अपरान्ह की नमाज अदा करने के बाद कारों के क्रेता-विक्रेता अल नसीम के कार बाजार में आ जुटते हैं। रियाद नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, "शुक्रवार सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन यहां सैकड़ों कारें खरीदी और बेची जाती हैं और लाखों रियालों (सऊदी मुद्रा) का वारा-न्यारा हो जाता है।"

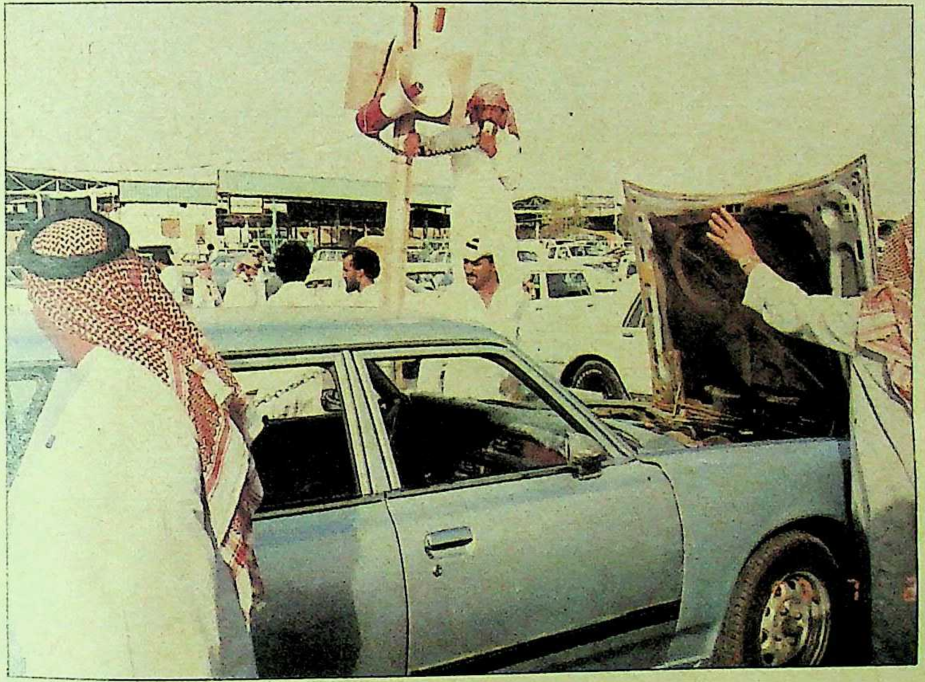
एक मोहरेज (नीलामीकर्ता) माइक्रोफोन से कार की बोली बोलता हुआ

पश्चिम एशिया में मंदी का दौर आने से पहले तक अल नसीम का कार बाजार दुनिया भर के कार-शौकीनों का स्वर्ग था। तब कारें आज के मुकाबले बहुत सस्ती हुआ करती थीं। लेकिन आज जापानी मुद्रा 'येन' के बेहद मजबूत हो जाने के कारण नयी व पुरानी दोनों किस्म की कारों की कीमतें बढ़ गयी हैं। यहां तक कि वे अरब खरीदार जो पहले सीधे शो-रूम से नयी कारें खरीदा करते थे, अब वे भी पुरानी कारें खरीदने लगे हैं। पुरानी कारों की मांग भी बढ़ रही है। पांच साल पुरानी निशान सनी ७ हजार रियाल (२१ हजार रुपए) में या दो साल पुरानी टयोटा कोरोल्ला को खरीदार खुशी-खुशी १७ हजार रियाल (५१ हजार रुपए) में खरीद लेते हैं।

हाल ही में के० मैथ्यू ने इस कार बाजार से निशान लारेल कार खरीदी है। उनका कहना है, "अल नसीम ने अनेक लोगों का सपना साकार किया है। मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं २५ हजार रियाल (७५ हजार रुपए) की कीमत की कार खरीद सकूं। अत: मेरे पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था कि मैं पुरानी कार खरीदूं। कीमतें बढ़ जाने के बावजूद कारें यहां सस्ती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में आपको पांच वर्ष पुरानी निशान कार १८ हजार रुपए में मिल जायेगी, लेकिन रियाद में यह संभव है, वहां आपको कार के मामले में किसी प्रकार का मलाल करने की जरूरत नहीं।"

—जॉय राफेल

निजी बातचीत से कारों का सौदा

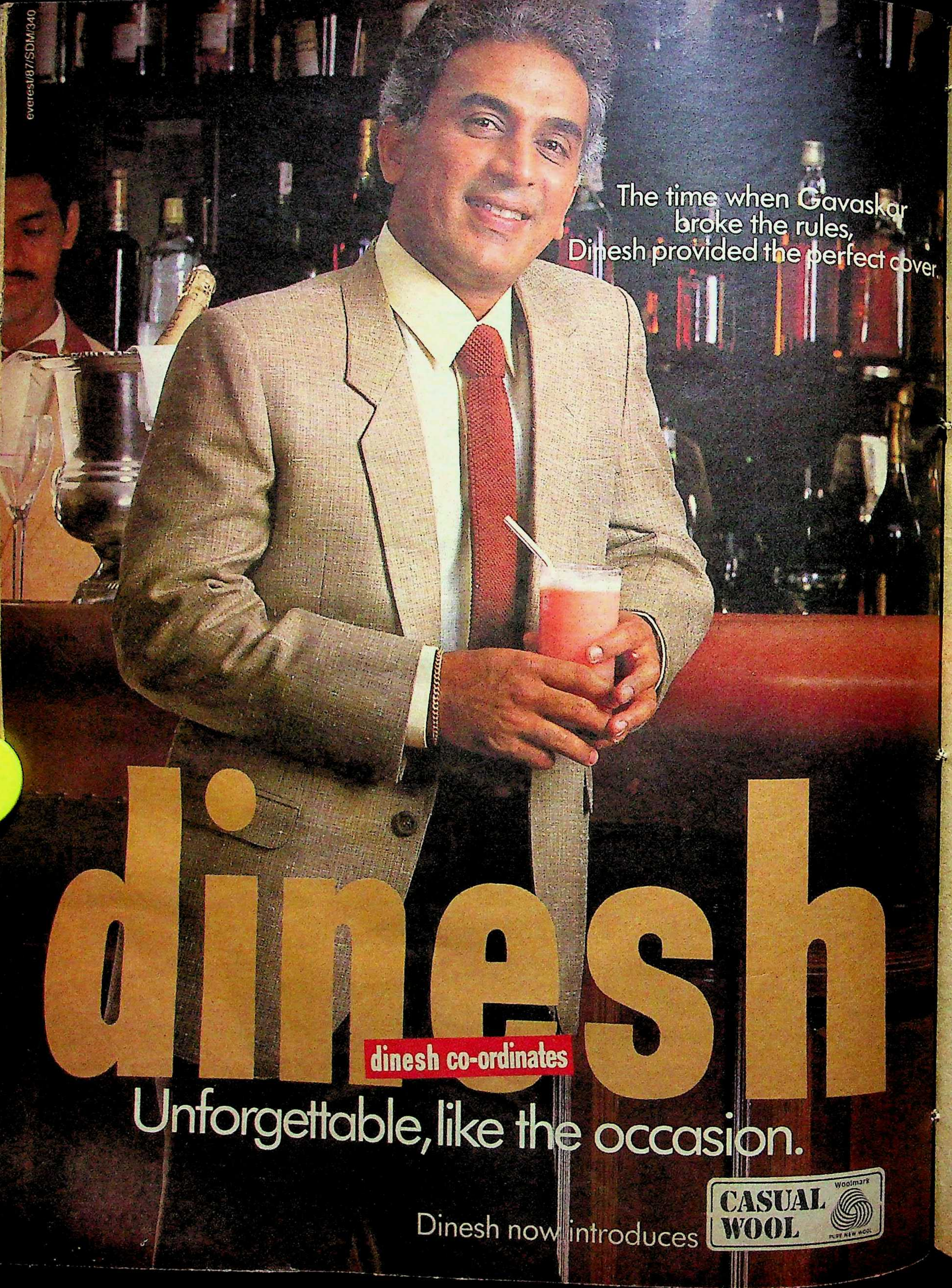
everest/87/SDM/340
The time when Gavaskar
broke the rules,
Dinesh provided the perfect cover.
dinesh
dinesh co-ordinates
Unforgettable, like the occasion.
Dinesh now introduces
CASUAL WOOL
Woolmark
PURE NEW WOOL

रियाद में भारतीय

खाड़ी के देशों में सऊदी अरब की राजधानी रियाद ही वह स्थान है, जहां सर्वाधिक भारतीय बसे हुए हैं। रियाद में ऐसा क्या आकर्षण है कि अपने घर से तीन हजार किलोमीटर दूर पहुंच कर भी कोई भारतीय वापस आना नहीं चाहता ?

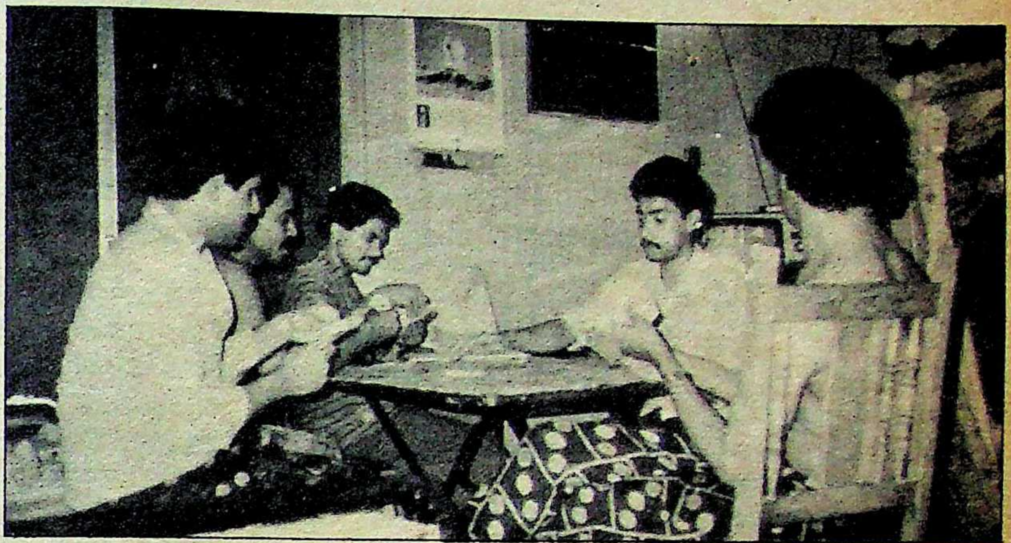

सिर्फ काम ही नहीं मनोरंजन भी : रियाद में भारतीय ताश खेलते हुए

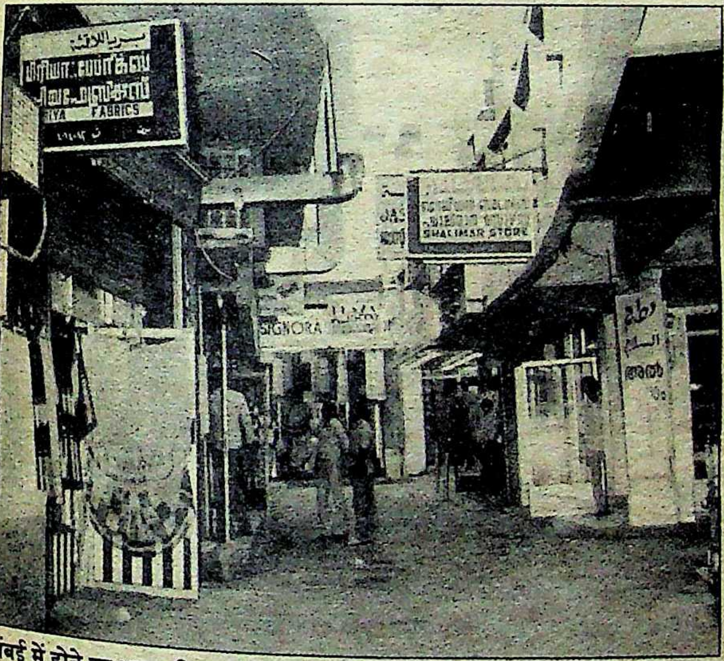

बंबई में होने का भ्रम : रियाद की दुकानों पर मलयालम के नामपट्ट

बेहद गर्म मौसम के बावजूद भारतीयों के लिए रियाद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तपते सूरज से उनके उत्साह में कमी नहीं आती। सीमेंट ग्लास और स्टील के जंगल जैसा दिखायी देता, यह शहर भारत के कोने-कोने से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। वे सभी यहां बड़ी आशाओं और महत्वाकांक्षा के साथ आते हैं। कोई उद्योगपति यहां के समस्यारहित माहौल में किसी के साथ साझे में कोई कारबार शुरू करने की तलाश में है, तो किसी व्यवसायी को किसी ईमानदार अरब व्यवसायी से कोई सौदा कर लेने की उम्मीद है। एक डाक्टर रियाद के अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित अस्पतालों में कार्य करने का सपना देखता है, तो बेरोजगार नवयुवक यहां ऐसे ऊंचे वेतन की उम्मीद मे चले आते हैं, जिसकी भारत में कल्पना तक नहीं की जा सकती। अधिकांश लोगों के सपने यहां पूरे होते हैं और भारत से दूर रहते हुए भी यहां वे अपने घर जैसा माहौल पाते हैं।

समस्या रहित माहौल : सऊदी अरब में विद्युतीकरण की परियोजनाओं से सम्बद्ध बंबई उपनगर विद्युत आपूर्ति लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक ए०ए० अरोसकर का कहना है, "यहां कार्य करना एक महान अनुभव है। भारत के विपरीत यहां कार्य करते हुए मुझे शायद ही कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। यहां का माहौल वास्तव में बहुत भिन्न है।" बहुत से भारतीय भी अरोसकर जैसी बातें बताते हैं।

अरोसकर ने बंबई विद्युत आपूर्ति विभाग में दस वर्षों तक कार्य किया है। उस दौरान वह अकसर लाइलाज समस्याओं से परेशान रहते थे। उनकी मान्यता है, "भारत में आपका साबका ऐसी विशाल नौकरशाही से पड़ता है जो भ्रष्ट अधिकारियों से भरी पड़ी है। यदि अमरीका से आपको भारत में कोई जरूरी उपकरण मंगाना है, तो असीम बंदिशों के कारण उसके यहां पहुंचने में छह से आठ महीने का समय लग जाता है, लेकिन रियाद में आप सिर्फ टेलेक्स भेजिये, डी०एच०एल० तीन दिन में वह उपकरण हाजिर कर देगी।"

कड़े कानून : वहां कामगारों की व्यवस्था करना भी सरल है। चूंकि कानून कड़े हैं, इसलिए कर्मचारी वहां

यहां की बात ही कुछ और है : विनोद मेनन और उनकी पत्नी अपने घर में

हड़ताल नहीं कर सकते। अरोसकर बताते हैं, "कर्मचारी वापस भेज दिये जाने के भय से एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं करते। वास्तव में वहां लोगों को काम करने में मजा आता है, क्योंकि वहां कार्य बड़े व्यवस्थित तरीके से होता है।" अरोसकर का कहना है कि रियाद पहुंचने के बाद ही अनुशासन के महत्व का पता चलता है। कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा करना होता है अन्यथा भारी जुर्माना हो सकता है। इसका असर यह होता है कि अनुशासन की अहमियत बढ़ जाती है और धीरे-धीरे यह लोगों की आदत में शुमार हो जाता है।

बंबई विद्युत आपूर्ति विभाग के परियोजना प्रबंधक उस दिन से भयभीत हैं, जब उन्हें भारत लौटकर जाना पड़ेगा। उनकी मान्यता बन चुकी है, "वहां के हालात बड़े अजीबोगरीब हैं। यदि किसी परियोजना में विलंब होता है, तो दोषी व्यक्ति घूस देकर या राजनीतिक दबाव डलवाकर बच जाता है।" किंग खालिद मिलिटरी अस्पताल में कार्यरत डा० नरेश शर्मा भी अरोसकर के विचारों से सहमत हैं। उनका कहना है, "डाक्टर के रूप में यहां काम करना बड़ी बात है। यहां तकनीक इतनी विकसित है कि मैं कह सकता हूं कि भारतीय अस्पतालों में यहां जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के पहुंचने में अभी एक दशक का समय लग जायेगा।"

कनिष्ठ स्तर पर कार्य करने वाले के०टी० अब्दुल्ला जैसे भारतीय भी श्री अरोसकर और डा० शर्मा से सहमत हैं। अब्दुल्ला यहां एक टाइल फैक्ट्री में पिछले दो सालों से काम कर रहा है और वह अपने काम से पूर्ण संतुष्ट है। वह बताता है, 'यह बेहतर तकनीक का कमाल है जिसने यहां सब कुछ बदल दिया है। भारत में तो हर काम हाथ से करना पड़ता है और मामूली से मेहनताने में कमर टूट जाती है।"

सरस जीवन : ऐसा नहीं है कि रियाद में सिर्फ काम-ही-काम है और आराम नहीं। यद्यपि यहां सिनेमाहाल और क्लब नहीं हैं, लेकिन यहां लोगों का सामाजिक जीवन जीवंत है। एक भारतीय राजनयिक की पत्नी शैला का कहना है, "यह

रियाद में लघु भारत

रियाद में बहुत कुछ भारतीय है। चाशनी में भीगी गरम-गरम जलेबियां, मसालेदार व्यंजनों की खुशबू, अगरबत्ती की महक और हिंदी एवं मलयालम के लोकप्रिय गीत ही नहीं, बल्कि कहीं-कहीं तो बंबई और दिल्ली जैसा नजारा भी वहां देखने को मिल जाता है, जिन्हें देखकर आपको यह अहसास ही नहीं होगा कि आप अपने घर से तीन हजार किलोमीटर दूर हैं। रात में बाथा और हारा की सड़कों पर चलते हुए हिंदी और मलयालम के विशाल चमकते विज्ञापन पटों को देखकर तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कहीं आप बंबई के माटुंगा इलाके में तो नहीं घूम रहे।

भारतीय भोजन : हारा रियाद में एक लघु भारत है। ऐसा ही बाथा भी है। यहां की हर चीज भारतीय है और यही वे इलाके हैं, जहां अपने घर की यादों में डूबे अधिकांश भारतीय रहते हैं। यदि कोई युवक नूडल्स, हेम्बर्गर , डबलरोटी आदि खाते-खाते ऊब गया हो, तो सांभर के साथ 'मसाला डोसा' के लिए वह हारा के मुगल और बाथा के ताज रेस्टोरेंट चला जायेगा।

बाथा के अल सलाम होटल में तो दाल, चावल, सब्जी-चपाती, कढ़ी, पापड़, चटनी, मटनकरी आदि से युक्त संपूर्ण भारतीय भोजन हर वक्त उपलब्ध है। यहां उपमा, इडली जैसे केरल के खास व्यंजन भी परोसे जाते हैं—वैसी ही महक और वैसे ही स्वाद के साथ। समीप ही है, कूपर रेस्टोरेंट—यहां खासकर केरल के समुद्री भोजन-प्रेमियों के लिए सब कुछ उपलब्ध है। ताजे झींगों की रसेदार सब्जी, प्राम्फेट मछलियां आदि। मनपसंद भरपेट भोजन के बाद आपको वहां पान भी मिलेगा। हारा में तो पान की भरपूर दुकानें हैं।

हारा और बाथा—दोनों स्थानों पर किराने की बड़ी अच्छी दुकानें हैं, जहां पापड़ से लेकर अचार-मसालों तक सभी भारतीय सामान मिलते हैं। यहां 'बेडेकर' और 'हवाई जहाज मार्का' अचार सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। सभी प्रकार की दालें, सूखी मछलियां, हरा धनिया-पोदीना के साथ ताजी सब्जियां, गेहूं और चावल इन दुकानों में हर वक्त मिलता है। केरल की लोकप्रिय दिनेश और गणेश छाप बीड़ियां यहां खूब चलती हैं।

कपड़ों के लिए किसी भारतीय को कोरियाई या जापानी कपड़ों की दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रिय टेक्सटाइल्स एवं ताज टेक्सटाइल्स जैसी भारतीय नामों की दुकानों में विमल्स, रेमण्ड्स आदि के 'मेड इन इंडिया' वस्त्र मिल जाते हैं। भारतीय कपड़े भारत के मुकाबले रियाद में कहीं अधिक सस्ते मिलते हैं। नये फैशन में विमल का एक पैंट का कपड़ा वहां ५० रियाल (करीब १५० रुपए) में मिल सकता है। एक भारतीय साड़ी जिसकी कीमत भारत में तीन सौ रुपए से अधिक है, वह यहां ५० रियाल में उपलब्ध है।

भारतीय संगीत : भारतीय फिल्मों के शौकीन यहां हर नयी-पुरानी फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। बाथा में तो अनेक वीडियो की दुकानें केवल भारतीयों के लिए ही हैं। ताज वीडियो की दुकान में हिंदी और मलयालम फिल्मों के सर्वाधिक वीडियो कैसेट हैं। 'सत्यमेव जयते' और 'इंसाफ' जैसी नयी फिल्मों के भारत में प्रदर्शित होने से पहले ही उनके वीडियो कैसेट बाथा में पहुंच जाते हैं।

बहरहाल, मलयालम की नयी फिल्मों के कैसेटों के यहां पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। केरल में प्रदर्शित होने के कम-से-कम तीन मास बाद ही नयी मलयालम फिल्में यहां पहुंच पाती हैं। यहां सबसे अधिक मांग तो उन वीडियो कैसेटों की है, जिनमें मुकेश और लता द्वारा गाये पुराने फिल्मी गीत होते हैं।

रियाद में अंग्रेजी और अरबी संगीत का अपना अलग ही आकर्षण है, लेकिन भारतीय संगीत से उसकी वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

मलयालम और हिंदी के संगीतप्रेमी भारतीय संगीत ही अधिक पसंद करते हैं। बाथा की संगीत दुकानें मलयालम, तमिल और हिंदी के लोकप्रिय नये-पुराने गीतों के कैसेटों से अटी पड़ी हैं। हारा की पतली गलियों में घूमते हुए आपको लता द्वारा गाये गीत के बोल सुनायी दे जायेंगे। हो सकता है, इससे आकृष्ट होकर आप कैसेट खरीदने के लिए संगीत की किसी दुकान पर पहुंच जायें।

बाथा में कुछ ही दुकानें ऐसी हैं, जहां अंग्रेजी और अरबी की पत्र-पत्रिकाएं मिलती हैं, अन्यथा प्रायः सारी दुकानें भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं बेचती हैं। 'टाइम्स आफ इंडिया' और 'मलयालम मनोरमा' वहां बेहद लोकप्रिय हैं। 'स्टार एण्ड स्टाइल' और 'स्टारडस्ट' तो वहां पहुंचने के कुछ ही घंटों में हाथो-हाथ बिक जाती हैं। मलयालम की 'केरल-कौमुदी' और 'मंगलम' पत्रिकाएं भी वहां काफी पसंद की जाती हैं।

हारा और उसके निकट स्थित बाथा के इलाके बंबई की याद ताजा कर देते हैं। यहां किसी भारतीय को अंग्रेजी या अरबी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां के अधिकांश दुकानदार और दुकानों के मैनेजर केरल के हैं। ठेठ अरबी दुकानदार भी इतनी हिंदी तो जानते ही हैं कि आपको वस्तुओं के दाम बता सकें, यहां तक कि उनके साइन बोर्ड भी मलयालम, तमिल और हिंदी में होते हैं। हारा भारत से दूर, एक भारत है। बाथा के साथ ही हारा २० लाख की आबादी वाले रियाद शहर का एक भारतीय कस्बा जैसा ही लगता है। इन दोनों इलाकों का भारतीय परिवेश देखकर आपको बरबस अपने घर की याद आ जायेगी और आप भारी हृदय से वास्तविक भारत पहुंच जाना चाहेंगे—जो यहां से दूर, बहुत दूर है। **—जॉय राफेल**

सच है कि महिलाएं अपने पतियों के बगैर बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन यहां जीवन नीरस नहीं है। जब उनके पति दूतावास चले जाते हैं, तो वह अपनी पुत्री शोभा के साथ घर पर रहती हैं। शोभा पत्रकार रह चुकी हैं। उनके साथ शैला की पुत्रवधु गिरिजा भी रहती हैं। ये सब घर में सफायी, भोजन बनाने और पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती हैं। शैला का कहना है कि पता ही नहीं चल पाता कि दिन कैसे व्यतीत हो जाता है। शामें घर पर मित्रों के साथ या मित्रों के घरों पर गुजरती हैं।

शैला सिह पोर्ट लुई और लुसाका में भी रह चुकी हैं, लेकिन उन्हें रियाद सबसे अलग लगता है। उनके अनुसार, "रियाद में कोई भिखारी नहीं है, सड़कों पर गंदगी नहीं रहती। यहां इतनी समृद्धि है कि चारों ओर हर चीज साफ-सुथरी नजर आती है।" शैला सिह बड़े प्रशंसा भाव से कहती हैं कि सऊदी अरबों के जीवन का एक और पक्ष उन्हें बहुत अच्छा लगता है—वह है, त्वरित न्याय। "यहां अपराधी के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि भारत में स्थिति बिलकुल दूसरी है।"

'दैनिक रियाद' समाचार पत्र में राष्ट्रीय मामलों के स्तंभ के संपादक विनोद मेनन की पत्नी नलिनी जैसी गृहिणियां भी यहां के शांत जीवन से खुश हैं। श्री मेनन जब दफ्तर में रहते हैं, तो वह घर पर अपना समय अपने पांच मास के बच्चे की देखभाल करने, पढ़ने और भोजन बनाने में व्यतीत करती हैं। उनका कहना है, "भारत में अपने बच्चे की देखभाल के लिए इतना समय दे पाना, मेरे लिए कठिन हो जाता और न ही मैं वहां इतनी पुस्तकें पढ़ पाती।" शाम को वे अकसर कार से घूमने जाते हैं और ड्राइविंग का आनंद उठाते हैं। मेनन बताते हैं, "हम दोनों को ड्राइविंग में बड़ा आनंद आता है। यहां ड्राइविंग कितना मजा देती है। खुली और साफ सड़कें हैं, बंबई की भीड़भरी सड़कों के मुकाबले यहां ड्राइविंग की बात ही कुछ और है।"

भारत से वहां पहुंचे युवक भी अपने ढंग से जीवन को सरस बनाकर रखते हैं। अधिकांश युवक केरल से हैं। केरल में उन्हें कोई काम मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहां न केवल अच्छी नौकरी मिली हुई है, बल्कि उन्हें इतना अच्छा वेतन भी मिलता है कि वे अच्छी-खासी रकम भारत भेज सकते हैं। के०टी० थामस का उदाहरण लें। थामस पिछले तीन वर्षों से खाद्य उपकरणं कंपनी में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा है और तीन वर्षों में उसने इतना कमा लिया है कि उसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। साथ ही रियाद में जीवन नीरस भी नहीं है। इस शहर में उसके अनेक मित्र हैं जो अकसर शाम को उसके घर आ जाते हैं, गप्प-शप्प होती है, ताश खेलते हैं या वीडियो देखते हैं।

काम का आर्कषण : थामस की तरह ही केरल के कुंडोटी इलाके का मोहम्मद अली यहां तकनीशियन है। उसका कहना है, "भारत में कार्य करने में मुझे कभी मजा नहीं आया। यहां आने के बाद मुझे पता चला कि काम करना भी खुशगवार हो सकता है। अब मेरी तो यही इच्छा है कि जितने अधिक समय तक यहां रह पाना मुमकिन हो, मैं रुक सकूं।" पास बैठे उसके दोस्त नजीर और अबूबकर भी थामस की बातों का समर्थन करते हैं। अबूबकर कहते हैं, "केवल धन का लोभ ही हमें यहां खींचकर नहीं ले आया, बल्कि यहां काम करने का अपना ही मजा है। मैंने काफी पैसा बचा लिया है और अब मैं वापस जा सकता हूं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि भारत में काम करने का ऐसा अच्छा माहौल नहीं मिल सकता।"

रियाद में अबूबकर के समान अनेक भारतीय हैं, जिन्होंने पर्याप्त धन जोड़ लिया है, लेकिन वे भारत वापस जाना नहीं चाहते। सुब्रमण्यम ने अकाई रैफल लाटरी का ५ लाख सऊदी रियाल (करीब १७ लाख रुपए) का पुरस्कार जीता है, लेकिन वह भारत लौटना नहीं चाहता। वहां, अन्य अनेक भारतीयों के समान उसे भी रियाद के व्यवस्थित माहौल में काम करने में राहत महसूस होती है। और यही वजह है कि रियाद में बसे भारतीय अपने घर की यादों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं।

—जॉय राफेल

नया... हैरत अंगेज़!

मुफ़्त आजमाइश प्रस्ताव.

बुलवर्कर का

पावर फ्लेक्स

आपके शरीर को सुगठित, खिलाड़ी सा चुस्त-तंदुरुस्त बनाये—तेज़ी से!

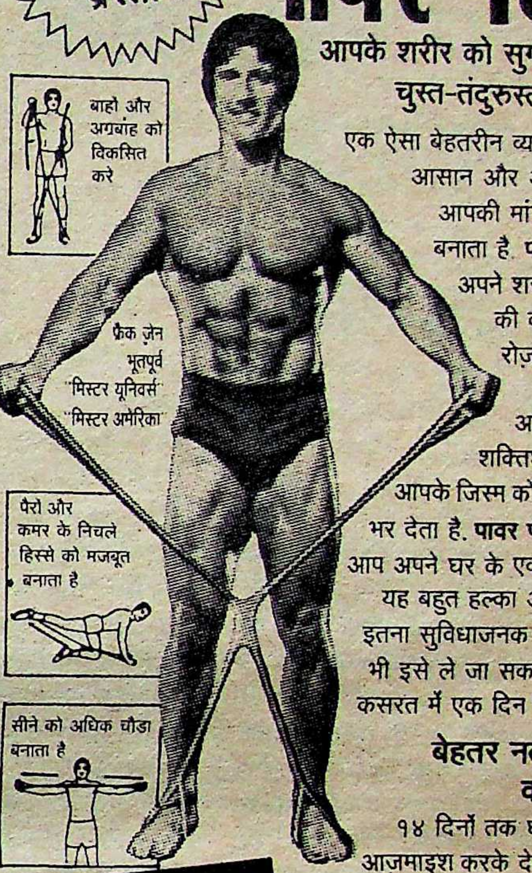
बाहों और अग्रबांह को विकसित करे
फ्रैंक ज़ेन
भूतपूर्व
"मिस्टर यूनिवर्स"
"मिस्टर अमेरिका"
पैरों और कमर के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है
सीने को अधिक चौडा बनाता है

एक ऐसा बेहतरीन व्यायाम साधन जो बहुत आसान और असरकारक तरीके से आपकी मांसपेशियों को मज़बूत बनाता है. **पावर फ्लेक्स** से आप अपने शरीर की हर मांसपेशी की वर्जिश कर सकते है. रोज़ाना सिर्फ १५ मिनिट की कसरत से यह आपकी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है, और आपके जिस्म को मर्दानी खूबसूरती से भर देता है. **पावर फ्लेक्स** का इस्तेमाल आप अपने घर के एकांत में कर सकते है. यह बहुत हल्का और लाने ले जाने में इतना सुविधाजनक है कि आप सफ़र में भी इसे ले जा सकते हैं, ताकि आपकी कसरत में एक दिन की भी बाधा न पड़े.

बेहतर नतीजों की गारंटी वर्ना पैसे वापस!

१४ दिनों तक घर पर इसकी मुफ्त आज़माइश करके देखिए. फिर भी अगर आप किसी वजह से नतीजों से पूर्ण संतुष्ट न हों तो सारी चीजें हमें लौटा दीजिये. हम आपका पैसा वापस कर देंगे. (डाक एवं पैकिंग खर्च काटकर)

हजारों पावर फ्लेक्स रु.१९८ में बिक चुके है

और अब सिर्फ १६० रु. में

जल्दी करें! यह प्रस्ताव सीमित अवधि के लिए है!

साथ में मुफ्त ३० रु. मूल्य का बैग, अगर आप १० दिन में जवाब देंगे.

अगर आपको किसी वजह से कूपन न मिल पाये तो आप नया पावर फ्लेक्स वी.पी.पी. द्वारा ऑर्डर देकर १६० रु. में इस पते पर मंगा सकते हैं: बुलवर्कर, मेहता महल १५ मैथ्यू रोड. बम्बई-४०० ००४

ABHA

यह कूपन आज ही भेजिए

बुलवर्कर, मेहता महल, १५ मैथ्यू रोड. बम्बई ४०० ००४. PF 01

जी हां. मुझे नया **पावर फ्लेक्स** बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम तुरंत भेज दीजिए. अगर १४ दिन के भीतर मै इसके नतीजों से खुश न हुआ तो मै सारी चीज़ें भेज कर पूरा पैसा वापस पा सकता हूं. (पैकिंग और डाक-खर्च निकालकर) कोई सवाल नहीं पूछा जायेगा मुझसे.

MY-55

कृपया सही खाने ☑ पर निशान लगाइए

☐ रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से भेजिए. मै १६० रु. का ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर/मनीऑर्डर नं.......... दि.................. संलग्न कर रहा हू. (बुलवर्कर प्राइवेट लिमिटेड को देय).

☐ वी.पी.पी. से भेजिए. डिलीवरी मिलने पर मै डाकिये को १६० रु. देने का वादा करता हूं.

नाम ....
पता ....
....
.... पिन .... हस्ताक्षर ....

साक्षात्कार/ **जी०एम० सैयद**

पाकिस्तान में 'जीये सिंध' के बुजुर्ग नेता

ज्यादातर पाकिस्तानी, हिन्दुस्तान को अच्छी निगाह से देखते हैं

जी०एम० सैयद

पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करनेवाला एक ही व्यक्ति है–जी०एम० सैयद। गुलाम मुर्तुजा सैयद यानी जी०एम० सैयद की जिंदगी विरोधाभासों से भरी हुई है। ८५ वर्ष की अवस्था में भी उनमें वही दमखम है, जो १९२३ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में था। वही चुनाव जीतकर आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। उसके बाद सैयद साहब ने महात्मा गांधी समर्थित खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। १९२४ में सिंध के लरकाना जिले में खिलाफत आंदोलन की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करके उन्होंने सिंध में अपनी धाक जमा दी, लेकिन खिलाफत आंदोलन को तुर्की में कमाल अतातुर्क द्वारा खिलाफत पद्धति की समाप्ति के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा। भारत में आंदोलन समाप्त हो गया। जी०एम० सैयद कांग्रेस में शामिल हो गये। सन् १९२५ में सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करने के आंदोलन में आपने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उसके बाद आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गये।

सन् १९२७ के असेंबली चुनाव में जी०एम० सैयद मुस्लिम लीग के टिकट पर सिंध असेंबली के सदस्य चुने गये। १९४६ में आपने ही सिंध असेंबली में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। उस वक्त जी०एम० सैयद पक्के मुस्लिम लीगी हो चुके थे, लेकिन उसके बाद ही उनका मोह-भंग हुआ। जिन्ना साहब से चुनाव के टिकट के मुद्दे पर मनमुटाव हुआ और जी०एम० सैयद का सियासी सितारा गर्दिश में आ गया। उसके बाद जब पाकिस्तान बना, तो समूचे पाकिस्तान में एक जबर्दस्त सियासी भूचाल आ गया। जिन्ना साहब (१९४८) और लियाकत अली खां (१९५४) की मौत के बाद मुस्लिम लीग भी तहस-नहस हो गयी। बाद में महज पांच-छह वर्षों के अंदर सात प्रधानमंत्री आये और चले गये। फिर १९५८ में अयूब खां ने फौजी हुकूमत कायम कर दी। तब तक सिंधु नदी का बहुत सारा पानी बह चुका था। जी०एम० सैयद को होश आते-आते बहुत वक्त गुजर चुका था। १९५२ में उन्होंने 'जीये सिंध आंदोलन' की बुनियाद डाली। जीये सिंध खालिस सिंधी राष्ट्रीयता की बात करता है। जी०एम० सैयद को इस मांग के बदले ३ वर्ष जेल में और २६ वर्ष घर में नजरबंद होकर गुजारने पड़े।

जनरल मुहम्मद जियाउल हक के शासन काल में उन्हें कुछ राहत मिली। इसीलिए इस वर्ष २५ फरवरी को सिंध में उनके गांव 'सन' में जीये सिंध के समर्थकों ने उनका ८५वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। हजारों सिंधी 'सन' में जमा हुए। 'सिंध देश, मेरा देश' और 'जीये सिंध' के नारे लगे। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत का प्रचार करनेवाले जी०एम० सैयद के जन्म दिवस पर जी-भरकर हवाई फायरिंग की गयी। बाद में जब वह बीमार पड़े, तो खुद जनरल जियाउल हक उन्हें देखने गये। बाद में जिया साहब ने उनके ऊपर लगी बंदिशों में ढील दी। उसी का नतीजा था कि वह अपने मित्र और बुजुर्ग पख्तून लीडर खान अब्दुल गफ्फार खां को देखने करांची से बंबई आये। पख्तून नेता सरहदी गांधी से तो उनकी गाढ़ी छनती है, लेकिन उनके बेटे और अवामी नेशनल पार्टी के सदर खान अब्दुल वली खां को वह पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा जी०एम० सैयद सिंध के दूसरे वामपंथी लीडरों (रसूल बख्श पलेजो, जाम साकी वगैरह) से भी नफरत करते हैं। बेनजीर भुट्टो और उनके स्व० पिता जुल्फिकार अली भुट्टो भी सैयद साहब की नजरों में पंजाब के एजेंट हैं। पंजाब के वह जानी दुश्मन हैं और सिंधियों की दुर्दशा का कारण पंजाबियों को ही मानते हैं। पहले वह मुहाजिरों से भी चिढ़ते थे, लेकिन पंजाबियों और पठानों से मार खाने के बाद मुहाजिरों ने स्वयं जी०एम० सैयद की शरण में आना शुरू कर दिया है।

जी०एम० सैयद ने कोई ५५ किताबें लिखी हैं। उनमें ३५ किताबों की बिक्री पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गयी है। आपने मुस्लिम सूफी मत और हिंदू वेदांत को एक नयी दिशा देने की कोशिश की है। इसीलिए पीरों, फकीरों और संतों के उपासक सिंधी उन्हें पीर का दर्जा देते हैं। वैसे भी सैयद होने के नाते सिंध में सामाजिक तौर पर उन्हें विशेष दर्जा हासिल है। उनके बंबई आगमन पर वहां की सिंधी बिरादरी ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। जगह-जगह उनका सम्मान किया गया। होटल में उनसे मिलने आनेवालों की भीड़ से घंटा भर का समय मांग कर 'माया' ने उनसे विशेष बातचीत की। प्रस्तुत हैं, जी०एम० सैयद से हुई बातचीत के कुछ अंश :

माया : यह अचानक आप हिंदुस्तान कैसे चले आये?

सैयद : खान बादशाह (सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां) की बीमारी को सुनकर चले आये। वह हमारे दोस्त हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने डटकर हिस्सा लिया। बाद में भी वह हमारी तरह पंजाबियों से लड़ते रहे। हमारी बीमारी पर पेशावर से करांची मुझे देखने आये थे, इसलिए मेरा भी फर्ज था कि उन्हें देखने आऊं। लेकिन अफसोस। वह मुझे बेहोशी की हालत में मिले।

माया : १९४६ में आपने पाकिस्तान के लिए आवाज उठायी थी। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गये?

सैयद : वह मेरी भूल थी। लेकिन कत्ल करने के बाद भी बीस साल की सजा मिलती है। मैं तो उस भूल की ४० साल से सजा काट रहा हूं। शुरू में मैंने समझा था कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंधियों के साथ इंसाफ होगा। उसके एवज में पहले तो मुहाजिरों (पाक में भारत से गये मुसलमान) ने और बाद में पंजाबियों ने सिंध को लूटना-खसोटना शुरू कर दिया।

माया : पंजाबी किस तरह सिंध को लूटते हैं?

सैयद : १९४७ में गैरसिंधियों की सिंध में ५-६ फीसदी आबादी थी। अब वह ४८ फीसदी है। पंजाब के फौजी जनरलों ने सिंध में बड़े-बड़े प्लाट एलाट करा लिये हैं। वह पंजाब से मजदूरों और किसानों को लाकर आबाद करते हैं। इसी तरह करांची में इस तरह के बिजनेस पर उनका कब्जा है। बैंक, रेलवे, तिजारत, सरकारी ओहदे, हवाई जहाज, इंश्योरेंस वगैरह में पंजाबी-ही-पंजाबी हैं। यहां तक कि पुलिस की नौकरियों पर भी उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। फौज में तो वह हैं ही।

माया : लेकिन सिंधियों को यह सब काम करने से किसने रोका है ?

सैयद : मौका मिले, तब वह कुछ करें।

माया : आपके 'जीये सिंध' से क्या मसला (समस्या) हल हो जायेगा ?

सैयद : आज नहीं, तो कल होगा ही। हमें उम्मीद है कि हमारी तहरीक (आंदोलन) एक-न-एक दिन जरूर कामयाब होगी।

माया : सिंध में दूसरे कई लीडर भी पाकिस्तानी सियासत में हैं। जाम साकी हैं, रसूल बख्श पलेजो हैं और सबसे बड़ी बात बेनजीर हैं, जो पाकिस्तान की लीडर हैं। आप सिर्फ सिंध की ही बात क्यों करते हैं ?

सैयद : ये लोग पंजाब के एजेंट हैं। लोगों को बहकाते हैं। सिंध पंजाब का गुलाम बन गया है। जाम साकी और पलेजो इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। आजकल वे लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिंध की सारी जमातें एक हो जायें। उनकी मुखालिफत करते हैं। असली बात यह है कि पंजाबी सियासतदां इन लोगों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। हम पंजाबियों के जुल्म से सिंध को आजाद कराना चाहते हैं। वह अस्सी फीसदी टैक्स सिंध से वसूल करते हैं और साठ फीसदी फौज पर खर्च करते हैं। हम सिंध को फौजी छावनी नहीं बनने देंगे।

माया : और बेनजीर ?

सैयद : वह भी वक्त के साथ बदल जाती है। अब यह खुद को सिंध की बेटी कहती है। वह सिर्फ जियाउल हक को हटाकर हुकूमत पर कब्जा करना चाहती है। सिंध के लिए उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके वालिद भुट्टो मरहूम ने ऐसा आईन (संविधान) बनाया था, जिसके जरिये सिंध पंजाब का गुलाम बना रहे। उनके आईन पर ही हमारे लड़कों ने उनके एक वजीर को हैदराबाद में पीटा था।

हम सिंध को फौजी छावनी नहीं बनने देंगे : (बांयें) जी०एम० सैयद

माया : आप खुद अपनी जमात 'जीये सिंध' के जरिये लोगों को एक नयी तहरीक (आंदोलन) के लिए क्यों नहीं आवाज देते हैं। वह कौन-सी बात है जो आपको इंकलाब करने से रोकती है ?

सैयद : मैंने सिस्टम बदलने के लिए आवाज दी है, लेकिन यह काम बिना पाकिस्तान टूटे नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास १० लाख फौज है। अमरीकी मदद है। हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। इंकलाब की आवाज देने पर खूनखराबा होगा। हम महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद (अहिंसा) पर यकीन करते हैं। सिंध के लिए हमारी एक लंबी लड़ाई है। आज नहीं तो कल हम जरूर कामयाब होंगे।

माया : लेकिन आप तो लोगों को जद्दोजहद के बजाय किताब लिखने का मश्वरा देते हैं।

सैयद : यह झूठ है। मेरे बारे में लोगों ने गलत बातें फैलायी हैं। मैंने कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जायें, दानिशवर (बुद्धिजीवी) एक जगह बैठकर अपने खयाल लिखें और लोगों को रोशनी दिखायें। यह बात मैंने ग्रीक फिलासफर प्लेटो के हवाले से कही थी। मेरे दुश्मनों ने यह बात उड़ा दी कि मैं लोगों से लड़ने के बजाय किताब लिखने को कहता हूं।

माया : नयी नस्ल के जवानों की सियासत से आप इत्तफाक (सहमत) करते हैं ?

सैयद : सिंध की नयी नस्ल लड़ने को तैयार है। लेकिन मैं उन्हें रोकता हूं। मैं गुरिल्ला जंग के खिलाफ हूं।

माया : आप एक तरफ 'जीये सिंध' की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जनरल जियाउल हक से भी आप मिलते हैं। इसी तरह एक जमाने में आप मुहाजिरों से भी नफरत करते थे। अब उन्हें भी दुआयें देते हैं।

सैयद : अब अगर कोई आपसे खुद मिलने आये, तो क्या आप उसे बिना मिले वापस कर देंगे ? जनरल जियाउल हक खुद मुझसे मिलने आये थे। मैं उन्हें कैसे मना करता ? पांच-दस मिनट बैठकर वह चले गये। एक बीमार आदमी को देखने के लिए आना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं ही खान बादशाह को देखने के लिए आया, तो क्या यह कोई बुरी बात है। रहा सवाल मुहाजिरों का, तो चूंकि अब पंजाबी उन्हें भी लूट रहे हैं, इसलिए वह मजलूम हो गये हैं। अब उनकी समझ में आ रहा है कि पंजाबी उन्हें भी नहीं छोड़नेवाले हैं। उनके लीडर अहताफ हुसैन मेरे पास आये थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि पंजाबियों के खिलाफ हम उनकी मदद करेंगे। शुरू में उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब मार पड़ने लगी, तो असलियत समझ में आ गयी है।

माया : पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल क्यों है ?

सैयद : यह पंजाबियों का काम है। वह लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी, हिंदुस्तान को अच्छी निगाह से देखते हैं। **—भेंट : फिरोज अशरफ**

जिंदा की गिरफ्तारी

एक महत्वपूर्ण सुराग

३० अगस्त को आखिरकार कुख्यात अपराधी हरजिंदर सिंह जिंदा पुलिस की पकड़ में आ ही गया। अनेक प्रमुख लोगों की हत्या और सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार एक लाख का इनामी अपराधी जिंदा पुलिस को जो कुछ बतला रहा है, उससे पुलिस विभाग का सिर चकरा रहा है, मसलन, ललित माकन और उनकी पत्नी की हत्या कर देने के बाद वह डेढ़ मास तक उत्तरी दिल्ली की एक बस्ती में रहा। इसी प्रकार अर्जुनदास की हत्या के बाद वह हत्या-स्थल से मात्र आधा किलोमीटर दूर आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मरीजों के तीमारदारों के बीच अनेक दिनों तक छुपकर रहा, जबकि दोनों मामलों में पुलिस यह मान रही थी कि वह दिल्ली छोड़कर भाग गया है। जिंदा कैसे गिरफ्तार हुआ और उससे पूछताछ में पुलिस को जो सूत्र मिल रहे हैं, उनके जरिये, क्या पुलिस आतंकवादियों की कमर तोड़ने में कामयाब हो सकेगी ?

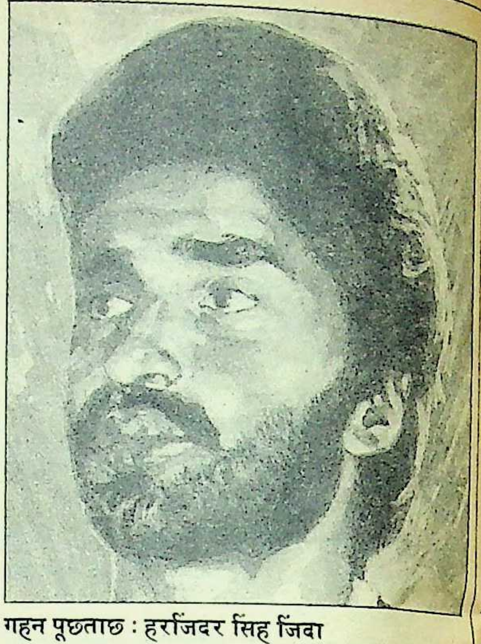
गहन पूछताछ : हरजिंदर सिंह जिंदा

दिल्ली से सटी उ०प्र० के गाजियाबाद जिले की फैक्टरियों के बीच बनी आवासीय बस्ती नोएडा में अब अचानक पुलिस और सेना के कई नये पहरे रचे गये हैं। पांच नयी चौकियां बनायी गयी हैं और लगभग हरेक घर को छानकर देखा जा रहा है कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता, जिसकी शिनाख्त के बारे में किसी को कोई संदेह हो।

यह हरज़िन्दर सिंह उर्फ जिंदा की गिरफ्तारी के बाद होनेवाली स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं में से एक है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त वेद मारवाह जिंदा की गिरफ्तारी को अब तक सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानते हैं।

गिरफ्तारी की योजना : ३० तारीख को सुबह पांच बजे दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में कई उपआयुक्त मौजूद थे। यह लगभग दुर्लभ मौकों पर होनेवाली बैठक थी, जिसमें स्पाटिंग-स्क्वायड के मुखिया जे०पी० सिंह भी मौजूद थे और बातचीत का विषय था, दिल्ली में कुछ कुख्यात आतंकवादियों की उपस्थिति के पक्के सबूत मिलना। बैठक में उपस्थित एक उपायुक्त के अनुसार उन्हें इस बात पर घोर आश्चर्य हुआ था कि आतंकवादियों की छुटपुट खबरों पर कार्रवाई टालने का निर्देश देनेवाले श्री मारवाह अचानक तेज कार्रवाई पर जोर दे रहे थे। इसका कारण भी फौरन साफ हो गया, जब श्री मारवाह ने जिंदा का नाम लिया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ पुलिस मुख्यालय में नहीं हो रही थी। पुलिस की विशेष शाखा के दो इंस्पेक्टर और पांच अन्य कर्मचारी पूरी रात जाग कर नोएडा और उत्तरी दिल्ली का चक्कर लगाते रहे और उन दो व्यक्तियों का पीछा करते रहे थे, जिनके उग्रवादी होने के बारे में उन्हें लगातार प्रमाण मिल रहे थे। ये दोनों उग्रवादी रिंग रोड से जानेवाली सड़क के उस हिस्से पर बार-बार आते-जाते देखे गये जो मजनूं का टीला नाम की जगह पर बने एक अपेक्षाकृत नये गुरुद्वारे की ओर जाता था। वहीं सादी वर्दी में पुलिस की विशेष शाखा के लोग तैनात थे। इन लोगों ने खास तौर पर जिंदा की दो हरकतों पर गौर किया। एक, तो वह गुरुद्वारे तक अकसर अकेला आता था और दूसरे, जाते वक्त उसके साथ कोई-न-कोई युवक होता था और स्कूटर या मोटर-साइकिल वही दूसरा युवक चला रहा होता था। इसके अलावा जिंदा से वहां मिलने के लिए भी बहुत सारे लोग आते थे। इनमें ज्यादातर युवक होते थे। नोएडा वाले घर, जो असल में एक कमरा और एक आंगन था, में जिंदा चार महीने में ज्यादा-से-ज्यादा सिर्फ छह-सात बार ठहरा और हर बार उसके साथ कोई-न-कोई होता ही था।

जिंदा और उसके साथी सतनाम सिंह की गिरफ्तारी उस आसानी से नहीं हुई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि, जिस दस्ते ने दोनों को पकड़ा, उसने आकस्मिक तरीके से हमला करने का पूरा ध्यान रखा था, लेकिन जिंदा को रिवाल्वर निकालने और उसे लोड करने का मौका मिल गया। दस्ते में मौजूद एक हेडकांस्टेबल अपनी पिस्तौल से जिंदा के पांव में पांच गोलियां न मारता, तो शायद इस अभियान की कहानी कुछ और हो जाती। गोलियां लगने के बाद भी जिंदा पूरी तौर पर सक्रिय था और एक इंस्पेक्टर को उसके ऊपर गिरकर उसे काबू में लेना पड़ा। अविश्वसनीयता की हद तक विचित्र बात यह है कि यह मुठभेड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के पास माल रोड चौराहे पर हुई, जहां सुबह दस बजे के उस वक्त दफ्तर जानेवालों की काफी भीड़ थी। चौराहे पर तैनात पुलिसवालों ने पूर्व सूचना के अभाव में इस सारे गुलगपाड़े को गुंडों का आपसी झगड़ा समझा और एक डायरी रिपोर्ट दर्ज करके अपने बड़े अधिकारियों को सूचना दी।

जिंदा को दिल्ली पुलिस ने दूसरी बार पकड़ा है और इस कारण दिल्ली पुलिस की धाक जम गयी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिंदा ने पूछताछ के दौरान यह मान लिया है कि फरारी के बीच उसके छिपने की जगहों में दिल्ली का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यहां भी उत्तर और दक्षिण दिल्ली में उसे लगातार शरण मिलती रही है। इस जानकारी पर चार लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है और इनमें से एक अकाली दल की युवा शाखा का भूतपूर्व पदाधिकारी है।

छापे : जिंदा और सतनाम को पकड़ने के बाद शुरू में जो जानकारियां मिलीं, उनके आधार पर मजनूं के टीला के पास ही एक परिवहन कंपनी के मालिक के एक खाली पड़े मकान पर छापा मारा गया और जिंदा के पास मिलीं चाबियों से जब मकान का एकमात्र पूरा बना कमरा खोला गया, तो अंदर से चीनी और अमेरिकी स्टेनगन, पिस्तौल, राइफल और पांच सौ से ज्यादा खाली कारतूस मिले। इस व्यापारी का कहना है कि उसने जिंदा को अपने एक रिश्तेदार के कहने पर मकान की चाबी दी थी और वह यह नहीं जानता था कि जिंदा वही आतंकवादी है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

रविवार को पुलिस की सारी ताकत जिंदा को छुपाये रहने में लग गयी। पहले उसे पांव से गोलियां निकलवाने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, पर वहां विशेष वार्ड में जगह न होने के कारण उसे पहले सेंट स्टीफन ले जाकर पांव से दो गोलियां निकलवायीं और बाकी गोलियों के लिए पुलिस अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान लगातार एक ऐसे आश्रय की तलाश थी जहां जिंदा से पूछताछ भी की जा सके और वह सुरक्षित भी रह सके। इस तलाश में एंबुलेंस में लदे नींद की गोलियां खाकर सोते हुए इस खतरनाक उग्रवादी को लाल किले के सैनिक अड्डे पर भी ले जाया गया, पर उस जगह पर भी पुलिस का मन नहीं माना। बाद में जिंदा कहां ले जाया गया है, इसकी जानकारी पुलिस के सब लोगों को नहीं है। सतनाम सिंह को पूछताछ के

लिए अशोक विहार थाने में ही रखा गया और जिदा को मुठभेड़ के बाद देखने का अवसर तक उसे नहीं मिला है। मजिस्ट्रेट को भी जिदा की रिमांड के लिए उसे रखे जानेवाली गुप्त जगह पर ही आना पड़ा।

जिदा का अतीत : १९८३ में मारपीट और चीजें छीनने के आरोप में आदतन अपराधी के रूप में पुलिस रिकार्ड में दर्ज हो जाने वाले जिदा की उम्र अब २८ वर्ष है। इस बीच उसने पुलिस की जानकारी के अनुसार तीस से ज्यादा बार पाकिस्तान की यात्रायें कीं और दो बार नकली पासपोर्ट पर विदेश जाने की भी कोशिश की। लेकिन एक बार पासपोर्ट जब्त हो जाने और दूसरी बार पुलिस मुठभेड़ हो जाने के कारण वह विदेश नहीं भाग सका। पुलिस फाइल में लिखे जिदा के परिचय का पहला पैरा पढ़ने लायक है—

"अकेले अपराध करने की आदतवाला युवक जिसे हर तरह के हथियार चलाने में कुशलता प्राप्त है। हिंदी, पंजाबी अच्छी तरह बोलता है और अंग्रेजी भी समझ लेता है। बातचीत में गालियां देता है और हत्याकांडों में खुद फायर करने पर जोर डालता है। रेल में पहले दर्जे में जाने की आदत भी इसे है।" लेकिन पुलिस फाइल में जो दो बातें दर्ज नहीं हैं, उनमें से एक है कि दिल्ली में एक सरकारी कालोनी में जिदा की एक प्रेमिका रहती है और उसके सगे चाचा दिल्ली के एक टाकीज में काम करते हैं। जिदा की प्रेमिका का नाम सबसे पहले अर्जुन दास हत्याकांड के बाद सामने आया था और उस समय पुलिस उसे आपराधिक सूची में डालकर गिरफ्तार करने के लिए गंभीर थी। इस बार की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि जिदा अपनी इस प्रेमिका से बाद में भी मिलता रहा है।

दुस्साहस : दिल्ली में जिदा का आतंकवादी कैरियर सर्वाधिक सफल रहा। जिन दो हत्याकांडों में उसकी तलाश सबसे ज्यादा जोरों से की जा रही थी, उनमें से एक अर्थात ललित माकन हत्याकांड के बाद जबकि पुलिस यह मान रही थी कि वह दिल्ली छोडकर भाग गया है, वह डेढ़ महीने तक उत्तरी दिल्ली की एक बस्ती में रहता रहा था। ललित और उनकी पत्नी गीतांजलि की हत्या के बाद ही जिदा के सिर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया और इसके कुछ ही दिन बाद उसने वापस दिल्ली में धावा बोलकर कांग्रेस-इ के नगर निगम पार्षद अर्जुन दास की हत्या कर दी। पता नहीं पुलिस को अब यह जानकर कैसा लग रहा होगा कि जिदा हत्या करने के बाद सिर्फ आधा किलोमीटर दूर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चला गया था और वहां मरीजों के तीमारदारों के बीच सोता रहा था। यह दुस्साहस भरे आत्मविश्वास से ही संभव हो सकता था।

जिदा ने दिल्ली को अपने सारे भावी अभियान का केन्द्र बनाया है, इस बारे में बार-बार सबूत मिल रहे थे। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष अरुण श्रीधर वैद्य की हत्या के बाद जिदा न सिर्फ दिल्ली आया, बल्कि अपने सूत्रों से विस्फोटक और हथियार जमा करके अपने शिष्यों में बांट गया। हालांकि शिष्यों की लापरवाही से जिदा के दिये हुए सारे हथियार पुलिस के पास पहुंच गये।

जिदा की गिरफ्तारी के अगले दिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम कर रही आतंकवादी सूचना इकाई ने दिल्ली पुलिस को एक नयी जानकारी दी। इसके अनुसार जिदा की इस दिल्ली यात्रा का एक मात्र उद्देश्य गृहमंत्री बूटा सिंह को उड़ाना था। इस जानकारी को इस बात से और बल मिला कि बूटा सिंह सप्ताह में कम-से-कम एक बार मजनूं के टीला गुरुद्वारे पर मत्था टेकने आते ही हैं। हो सकता है कि बार-बार इस गुरुद्वारे में जाकर जिदा अपने इसी खूनी अभियान की रूपरेखा बना रहा हो। लेकिन, हमले की सूची में सिर्फ बूटा सिंह नहीं थे, क्योंकि जिदा को पकड़ने के सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली पुलिस और गृहमंत्रालय ने दिल्ली में रहनेवाले सभी विशिष्ट और अतिविशिष्ट लोगों को सूचना भेजी थी कि वे किसी भी सार्वजनिक समारोह और भीड़भाड़ से फिलहाल बचें और जहां तक संभव हो; अपनी सुरक्षा के इंतजामों में कोई ढील न होने दें।

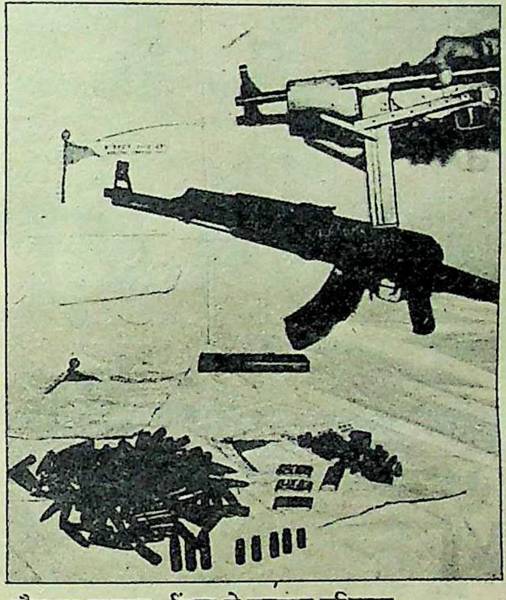

मौत का ताण्डव : जिदा के बरामद हथियार

पुलिस आयुक्त श्री वेद मारवाह ने 'माया' से कहा कि जिदा और उसके साथियों की दिल्ली में उपस्थिति की खबर मिल जाने के बाद, वे यह खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे कि आतंकवादी कहीं अपना हाथ आजमाने की सोचें। श्री मारवाह ने यह भी कहा कि जिदा की तरह के ही कुछ और आतंकवादी दिल्ली में लगातार आ-जा रहे हैं और उनके संपर्कों का पंजाब में पता लगना बहुत जरूरी है। इन संपर्कों की सूची पंजाब पुलिस को दी जा चुकी है।

सतनाम कौन है ? : सतनाम और जिदा दोनों स्वर्ण मंदिर के एक कमरे में मिले थे, जहां जिदा को संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की सिफारिश पर सबसे पहले रखा गया था। सतनाम वैसे तो इंटर पास है, पर बोलचाल में देहाती पंजाबी बोलता है। मोटर और ट्रक सुधारने का काम जानने के कारण उसे छुपने में भी आसानी होती है। सतनाम जिदा के साथ दिल्ली नहीं आया था, लेकिन दो महीने पहले ग्रेटर कैलाश में हत्याकांड करनेवाले लोगों में से एक करमजीत सिंह से उसका अच्छा परिचय था। पुलिस मानती है कि करमजीत को स्टेनगन दिलवाने में भी उसका हाथ है। जिदा और सतनाम में एक समानता और है। दोनों अपने को खालिस्तान कमांडो फोर्स के जनरल लाभ सिंह का शिष्य मानते हैं। लाभ सिंह अभी संभवत: पाकिस्तान में है।

जिदा की गिरफ्तारी के बाद उत्साहित दिल्ली पुलिस के सामने प्रश्नचिन्हों की कमी नहीं है। जैसे, गृहमंत्रालय के एक उपसचिव ने बाकायदा पत्रकारों से यह कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास जिस सरकारी एजेंसी ने जिदा की खबर पहुंचाई, उसको गिरफ्तारी अभियान में शामिल नहीं किया गया, इसकी शिकायत की गयी है। बाद में दिल्ली पुलिस की एक विज्ञप्ति में इस एजेंसी यानी इंटेलीजेंस ब्यूरो का नाम भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक ने भी दिल्ली पुलिस के पास भेजे एक तगड़े विरोध पत्र में कहा है कि इतने खतरनाक आतंकवादी के नोएडा में छिपे होने की खबर प्रमाणित हो जाने के बाद भी इलाके की पुलिस को सूचित नहीं करना जनजीवन के साथ खिलवाड़ है।

११० से अधिक मामले : जिदा को लेकर दिल्ली पुलिस की एक मुसीबत और है। जनरल वैद्य की हत्या की जांच एवं महाराष्ट्र और उदयपुर के दो पुलिस अफसरों के वध की पड़ताल करने, राजस्थान पुलिस दिल्ली पहुंच गयी है. लेकिन इन पंक्तियो के लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस ने दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को जिदा के दर्शन तक नहीं करने दिये हैं। इसकी भी शिकायत महाराष्ट्र पुलिस ने गृह-मंत्रालय में कर दी है। अभी गनीमत यही है कि दिल्ली पुलिस की सौतेली बहन की तरह रहनेवाली पंजाब पुलिस अब तक जिदा के बारे में पूछताछ करने दिल्ली नहीं आयी है। हालांकि, दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा चिंतित पंजाब से ही है, क्योंकि वहां जिदा के खिलाफ ११० से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं और इनकी पड़ताल के बहाने जिदा को ले जाने का अदालती आदेश आसानी से लिया जा सकता है। जिदा, लाभ सिंह के बाद नंबर दो था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब लाभ सिंह को अपने रिश्तेदार लाल सिंह और एक पुराने सहयोगी गुलाब सिंह पर भरोसा करना पडेगा और सिर्फ इसी स्थिति के चलते यह माना जा सकता है कि भूमिगत संगठन उतनी हिम्मत से काम नहीं कर पायेगा, जैसे जिदा के रहते करता रहा है। गुलाब सिंह की जांघ में बम फटने से हुआ घाव अभी भरा नहीं है और लाल सिंह की किसी गतिविधि का प्रमाण बहुत समय से नहीं मिला है।

—**विशेष प्रतिनिधि**

INDIAN EXPRESS
EMPLOYEES UNION

'इंडियन एक्सप्रेस' पर छापे

पोल खोलने की सजा

'इंडियन एक्सप्रेस' कार्यालय (नयी दिल्ली) पर छापे के दौरान पुलिस द्वारा नाकेबंदी

छाया : रंजन बसु

'इंडियन एक्सप्रेस' लगातार राजीव-सरकार की बखिया उधेड़ता रहा है। इसलिए हाल में एक्सप्रेस पत्र समूह पर पड़े छापों पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई है। इन छापों के पीछे सरकार का इरादा क्या रहा है? क्या गोयनका को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है?

कस्टम्स, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सी०बी०आई० के अधिकारी कर्मचारियों का दस्ता एक्सप्रेस बिल्डिंग प्रातः ६ बजे पहुंचा था। लगभग उसी समय जनसत्ता सम्पादक प्रभाष जोशी को बंबई से रामनाथ गोयनका फोन पर सूचित कर चुके थे कि छापा पड़नेवाला है।

ऐसी ही सूचना लगभग एक महीने पहले भी आयी थी। एक्सप्रेस पत्रसमूह के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ प्रमुख देशी-विदेशी पत्रकार पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे थे, किंतु उस दिन कोई छापा नहीं पड़ा था। इससे पहले १३ मार्च को इंडियन एक्सप्रेस पत्रसमूह के प्रसिद्ध मालिक रामनाथ गोयनका के दिल्ली के सुंदर नगर स्थित निवास पर वह बहुप्रचारित छापा पड़ा था, जिसके बाद से ही राजीव गांधी और उनकी सरकार एक संकट से दूसरे संकट से घिरती रही है।

शायद यही कारण था कि १ सितंबर के छापे की सूचना देते समय और छापे खत्म होने पर रामनाथ गोयनका जरा भी चिंतित नहीं थे। छापे देशभर में फैले हुए इंडियन एक्सप्रेस के ११ संस्करणों और रामनाथ गोयनका सहित समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों पर एक साथ पड़े थे।

बूढ़े गोयनका के जुझारू स्वभाव और अतीत को जाननेवालों के लिए उनका चिंतित न होना आश्चर्यजनक नहीं है। गोयनका को लड़ने में मजा आता है। जितना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी, उतना बड़ा आनंद। इस सबसे ताजी मुठभेड़ में गोयनका कितना आनंद उठा रहे हैं यह तो पता नहीं, लेकिन, १ सितंबर के अभूतपूर्व छापों ने पूरे देश में प्रबुद्ध वर्ग में आक्रोश की एक व्यापक लहर को जन्म दिया है।

प्रतिक्रिया : छापों की प्रतिक्रिया देशव्यापी, व्यापक और कड़ी हुई है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाचारपत्र, प्रत्येक विपक्षी नेता, प्रत्येक बुद्धिजीवी ने कठोरतम शब्दों में इस कदम की निंदा की है। आम प्रतिक्रिया यही रही है कि यह एक घबराहट में होश गंवा बैठी सरकार का आश्चर्यजनक रूप से मूर्खतापूर्ण और वहशियाना कदम था कि यह प्रेस की आजादी पर सीधा हमला था कि यह राजीव गांधी की मूल दमनकारी प्रवृत्ति का मूर्त प्रकटीकरण था कि यह सरकार के तानाशाही स्वभाव और इरादों का चिह्न था, आदि-आदि।

किंतु, स्वयं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर इस घटना पर दुख-मिश्रित विस्मय के साथ-साथ एक प्रश्न लगभग हर जगह पूछा जा रहा था, यह हुआ कैसे? इतने स्पष्ट रूप से आत्मघाती कदम उठाने की सलाह किस मेधावी मस्तिष्क ने प्रधानमंत्री को दी होगी?

प्रधानमंत्री को इसलिए कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाने का साहस अकेले रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग के महानिदेशक बी०वी० कुमार या उनके दूसरे प्रशासनिक सहयोगी कर ही नहीं सकते थे। दूसरे, यदि छापा मारनेवाले दस्तों में केवल डी०आर०आई० (डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) और कस्टम विभाग के ही लोग होते, तो माना जा सकता था कि आदेश वित्त मंत्रालय से आये होंगे, क्योंकि दोनों उसके अधीन हैं। किंतु उनमें सी०बी०

आई० के अधिकारी भी अघोषित रूप से शामिल थे। सी०बी०आई० गृहमंत्रालय के अधीन है।

कांग्रेस के एक प्रभावशाली अखिल भारतीय महामंत्री चकित थे, दुखी थे। 'माया' से कह रहे थे, "इस संकटपूर्ण समय में इससे अधिक आत्मघाती कदम की कल्पना नहीं हो सकती । यदि गोयनका में एक-दो नही हजार दोष भी हों, तो भी इस समय उसे नहीं छूना चाहिए था। चार-पांच महीने बाद जब माहौल थोड़ा सुधर जाता तब भी यह कार्रवाई की जा सकती थी।"

एक युवा सांसद का कहना था, "भारत की जनता गिरते को थामती है, प्रताड़ित के प्रति संवेदना दिखाती है। गोयनका पर इस समय इस तरीके से हमला करके सरकार ने उन्हें सहानुभूति और समर्थन का पात्र बना दिया है।" एक वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य ने कहा, "यदि छापों का उद्देश्य किन्हीं विस्फोटक दस्तावेजों या सूचनाओं को छपने से रोकना था, तो भी यह कदम व्यर्थ था। जो सूत्र एक्सप्रेस को एक बार दस्तावेज दे सकते हैं, वह दूसरी बार भी दे सकते हैं। इन छापों से जानकारी के स्रोत तो बंद नहीं हो सकते। एक्सप्रेस तो केवल माध्यम है और यदि उद्देश्य एक्सप्रेस पत्र समूह और उसके माध्यम से भारतीय प्रेस को धमकाना, दंडित करना था, तो भी यह कदम नितांत अदूरदर्शित था,क्योंकि इस एक कदम से प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रेस को अपने खिलाफ कर लिया है।"

छापों के सूत्रधार : 'माया' को मिली जानकारी के अनुसार इन छापों की योजना और अमल का श्रेय दो लोगों को जाता है। पहले, प्रधानमंत्री राजीव गांधी–सूत्रों के अनुसार जिनकी गोयनका और एक्सप्रेस संपादक अरुण शौरी के प्रति घृणा ने एक ग्रंथि का रूप ले लिया है। दूसरे, उनके सूचना सलाहकार मणि शंकर अय्यर–एक्सप्रेस सूत्रों का कहना है कि वित्तराज्यमंत्री गढावी ने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया था कि उनके पास गोयनका और उनके अखबारों को आर्थिक घपलों में फंसाने के लिए 'अचूक' आधार हैं और सरकार निश्चित होकर एक्सप्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

एक्सप्रेस सूत्रों के अनुसार उन्हें जुलाई के आरंभ से ही संकेत मिल गये थे कि 'एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट' ऐसी तैयारियां कर रहा है और किसी भी समय छापे पड़ सकते हैं।

ऐसे छापे आज तक किसी अखबार के कार्यालय पर नहीं पड़े। दिल्ली, बंबई, मद्रास, कोचीन, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, मदुरै, बड़ोदा, विजयवाड़ा और विजयानगरम–इन ११ स्थानों पर एक्सप्रेस समूह के अखबारों के कार्यालयों पर ३०० से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों और हजारों की संख्या में पुलिसजन १ सितंबर की सुबह अचानक प्रकट हो गये। छापों की तारीख भी महत्वपूर्ण थी। एक दिन पहले, ३१ अगस्त को ही राज्यसभा का मानसून सत्र समाप्त हुआ था। सूत्रों के अनुसार यह भी सुनियोजित था कि संसद के सत्र के तुरंत बाद ही छापे मारे जायें।

छापों की योजना को इतना गुप्त रखा गया था कि वित्त मंत्रालय में वित्तसचिव और राजस्व सचिव को छोड़कर किसी बड़े अधिकारी को इसकी पूर्वसूचना नहीं थी। यहां तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक को भी अंधेरे में रखा गया। एक सूत्र के अनुसार योजना का केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय था और विभिन्न विभागों के बीच सूत्रधार का काम संभाल रही थीं प्रधानमंत्री की सचिव श्रीमती सरला ग्रेवाल।

बहरहाल, मंगलवार को एक्सप्रेस के सभी ११ कार्यालयों में हंगामा रहा। छापा मार रहे अधिकारियों और अधिकांश जगहों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों, एक्सप्रेस कर्मचारियों के बीच भरपूर तनातनी रही, कहीं-कहीं धक्का-मुक्की हुई, पत्रकारों कर्मचारियों को धकेला-धमकाया गया, कई स्थानों पर फोटोग्राफरों के कैमरे छीन लिये गये और फिल्म रोल निकाले गये।

दिल्ली, बंबई, मद्रास जैसे बड़े नगरों में छापों के शुरू होते ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेस समुदाय वहां एकत्र हो गया। कई जगह इन बाहरी पत्रकारों और छापा मार रहे अधिकारियों में भी बड़ी झड़पें हुईं। दिल्ली में जनरल मैनेजर सुशील गोयनका ने तलाशी के सभी वारंटों की प्रति लिए बिना तलाशी लेने-देने से कड़ा इनकार कर दिया। मुख्य संपादक अरुण शौरी, एक्सप्रेस के प्रसिद्ध कानूनी सलाहकार गुरुमूर्ति वहीं उपस्थित थे। दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता मदनलाल खुराना अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहादुरशाह जफर मार्ग पहुंच गये। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और अरुण शौरी का भाषण हुआ।

प्रेस की आजादी पर शर्मनाक हमला : उत्तेजित अरुण शौरी

छाया : रंजन बसु

इतनी भीड़ और देशी-विदेशी पत्रकारों की उपस्थिति में जोर-जबर्दस्ती करने में असमर्थ एनफोर्समेंट दस्ता सुबह ६ बजे से प्रयासों के बावजूद शाम के ४ बजे ही तलाशी शुरू कर पाया, जब उसके अधिकारियों ने सुशील गोयनका को आवश्यक वारंट लाकर दे दिये थे।

उधर, चूंकि एक्सप्रेस समूह का मुख्य कार्यालय बंबई में है, इसलिए राजस्व अभिसूचना निदेशालय (डी०आर०आई०) के महानिदेशक बी०वी० कुमार स्वयं बंबई में बैठकर पूरी कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। बंबई में केवल एक्सप्रेस कार्यालय और गोयनका सहित वरिष्ठ अधिकारियों के घरों की ही नहीं, बल्कि उद्योगपति नसली वाडिया (बाम्बे डाइंग के मालिक) के दो सचिवों के घरों की भी तलाशी ली गयी थी।

आरोप : दिनभर के छापों के बाद बी०वी० कुमार ने शाम को एक वक्तव्य जारी किया। इसके अनुसार छपाई की मशीनों के आयात, उनके मूल्य की सही सूचना देने और उनके उपयोग में हेराफेरी और गलतबयानी करके एक्सप्रेस समूह ने कई कानूनों का उल्लघंन किया था। अगले दिन जारी दूसरे वक्तव्य में राजस्व अभिसूचना ने लंबे, विस्तृत ब्योरे के साथ दावा किया कि अब तक एक्सप्रेस समूह द्वारा विभिन्न तरीकों से की गयी ३३.५ लाख रुपये की कर-चोरी पकड़ी गयी है।

इसके उत्तर में एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की कर-चोरी देश के हर बड़े अखबारों ने की है, एक उद्योगपति (उनका संकेत रिलायंस उद्योग समूह के धीरूभाई अंबानी की ओर था) ने १०० करोड़ रुपए से अधिक की कर-चोरी की है, उन पर ऐसे छापे क्यों नहीं मारे जाते ?

बहरहाल, अब यह स्पष्ट हो गया है कि राजीव सरकार ने फेयरफैक्स और बोफोर्स जैसे स्कैण्डलों को उछालने के सजा के रूप में एक्सप्रेस पत्र समूह को 'छापों' के जरिये डराने और सताने की कोशिश की है, लेकिन पूरे देश के प्रेस की आजादी के पक्षधर आज गोयनका के पीछे खड़े हो गये हैं और इस समाचारपत्रसमूह के पत्रकारों का भी हौसला बुलंद है। एक्सप्रेस पत्रसमूह के सभी संस्करणों ने अपने अगले दिन के अंक के मुखपृष्ठों पर ही संपादकीय प्रकाशित कर यह संकल्प दोहराया है कि वे राजीव गांधी सरकार की जन व देश-विरोधी कारगुजारियों का हिम्मत के साथ आगे भी परदाफाश करते रहेंगे।

—राहुल देव

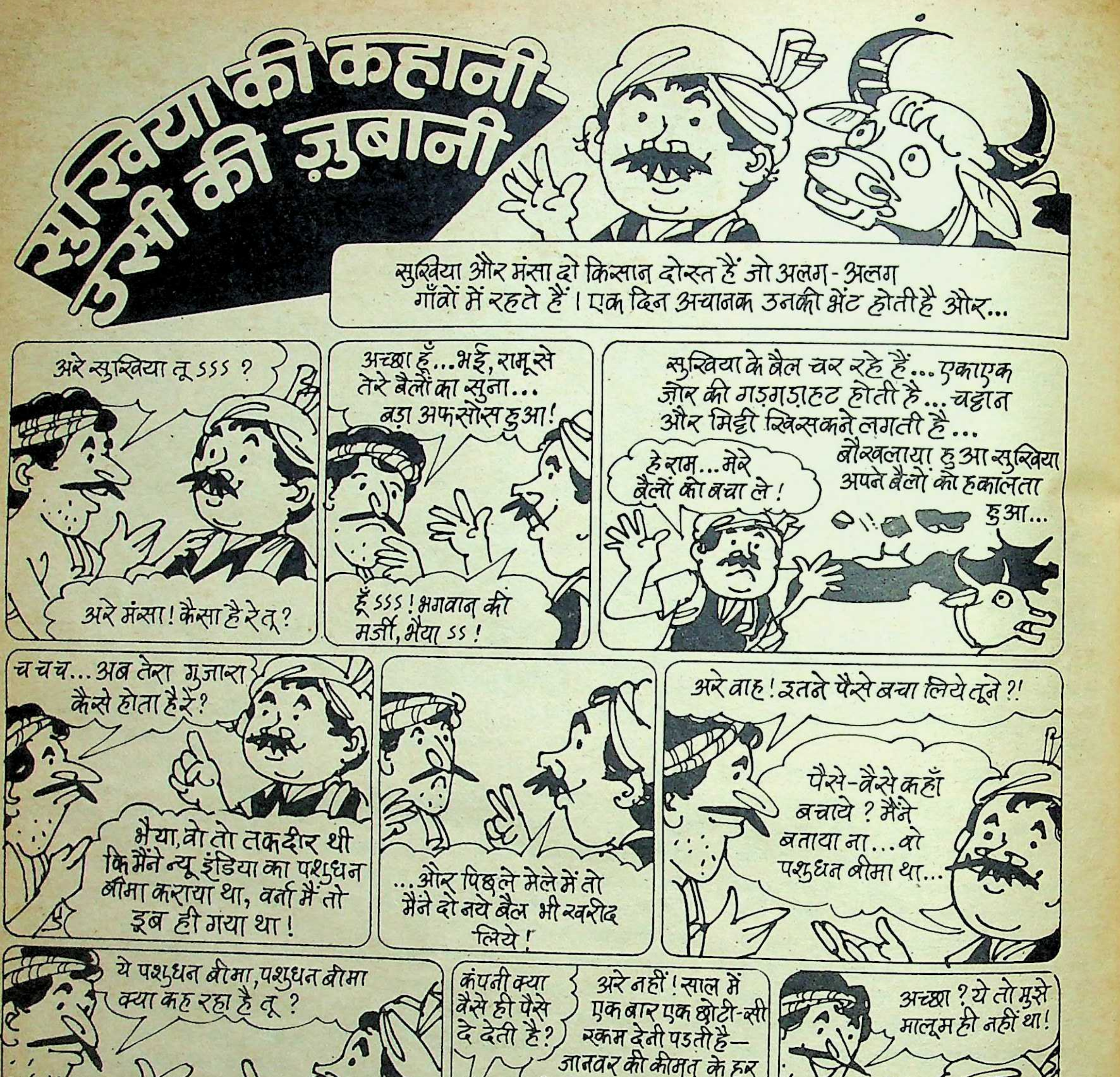
सुखिया की कहानी— उसी की ज़ुबानी
सुखिया और मंसा दो किसान दोस्त हैं जो अलग-अलग गाँवों में रहते हैं। एक दिन अचानक उनकी भेंट होती है और...
अरे सुखिया तू sss ?
अरे मंसा! कैसा है रे तू?
अच्छा हूँ...भई, रामू से तेरे बैलों का सुना... बड़ा अफसोस हुआ!
हूँ sss! भगवान की मर्ज़ी, भैया ss!
सुखिया के बैल चर रहे हैं...एकाएक ज़ोर की गड़गड़ाहट होती है...चट्टान और मिट्टी खिसकने लगती है...
हे राम...मेरे बैलों को बचा ले!
बौखलाया हुआ सुखिया अपने बैलों को हकालता हुआ...
च च च...अब तेरा गुज़ारा कैसे होता है रे?
भैया, वो तो तकदीर थी कि मैंने न्यू इंडिया का पशुधन बीमा कराया था, वर्ना मैं तो डूब ही गया था!
...और पिछले मेले में तो मैंने दो नये बैल भी खरीद लिये!
अरे वाह! इतने पैसे बचा लिये तूने?!
पैसे-वैसे कहाँ बचाये? मैंने बताया ना...वो पशुधन बीमा था...
ये पशुधन बीमा, पशुधन बीमा क्या कह रहा है तू?
पशुधन बीमा मतलब-अगर तुम्हारे ढोर-जानवर किसी दुर्घटना या बीमारी-वीमारी से मर जाएँ तो न्यू इंडिया बीमा कंपनी इस नुकसान की भरपाई पैसे देकर करती है।
कंपनी क्या वैसे ही पैसे दे देती है?
अरे नहीं! साल में एक बार एक छोटी-सी रकम देनी पड़ती है—जानवर की कीमत के हर १०० रु. पर ज़्यादा से ज़्यादा ४ रु., बस!
अच्छा? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था!
सच भैया... नुकसान के बखत, बीमा ही अपना सहारा है!
SAA/NIA/2802/HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इंडिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

न्यू इंडिया एश्योरेंस

(जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की एक सहायक कंपनी)

बीमा — नुकसान में आपका सहारा!

अब मोदी और बिड़ला में ठनी

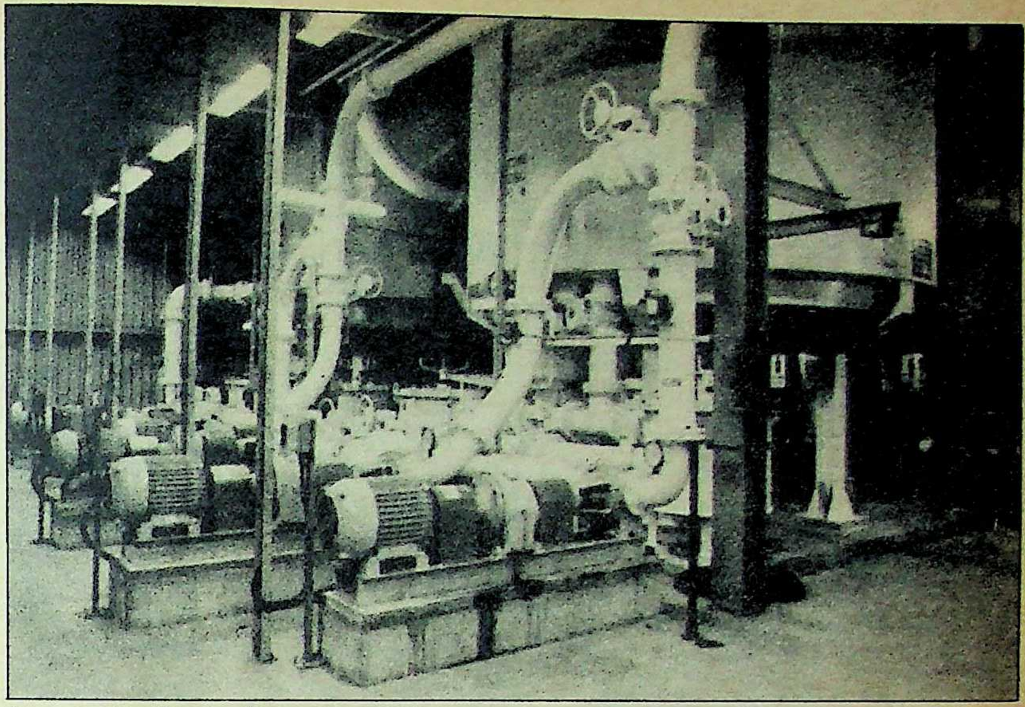

विवाद का केंद्र : विस्कोस स्टेपल फाइबर परियोजना

नसली वाडिया और धीरूभाई अंबानी की आपसी व्यावसायिक लड़ाई में तो पूरे देश की राजनीति ही उलट-पलट गयी और अब विस्कोस स्टेपल फाइबर परियोजना को लेकर बिड़ला और मोदी औद्योगिक घराने आपस में भिड़ गये हैं। यह लड़ाई क्या गुल खिलायेगी ?

देश के दो प्रमुख औद्योगिक घरानों-मोदी और बिड़ला में पिछले चार वर्षों से एक परियोजना पर लड़ाई चल रही है। यह तनातनी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला काफी तेज हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के बारे में इस साल के अंत तक निर्णय लिए जाने की आशा है, जिससे इस लड़ाई में हार-जीत का फैसला अब ज्यादा दूर नहीं ।

झगड़े की जड़ : दोनों पक्षों के बीच झगड़े की जड़ है—विस्कोस स्टेपल फाइबर परियोजना। इस लड़ाई में एक-दूसरे को ललकारने वाले योद्धा हैं—ग्रेसिम लि० के अध्यक्ष आदित्य विक्रम बिड़ला और मोदी फाइबर लि० के अध्यक्ष एस०के० मोदी। केन्द्र सरकार इसमें 'रेफरी' की भूमिका निभायेगी। मोदी १.१६ अरब रुपए की लागत से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में विशेष किस्म का विस्कोस स्टेपल फाइबर (वी०एस०एफ०) बनाने का कारखाना लगाना चाहते हैं। इस उत्पाद का इस्तेमाल सिंथेटिक कपड़े बनाने में होता है। मोदी को यह परियोजना लगाने संबंधी 'लेटर आफ इटेंट' (आशय पत्र) १८ जून, १९८३ को मिला, लेकिन चार साल बीतने के बावजूद केन्द्र सरकार ने अंतिम स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि कई सवाल-आपत्तियां मुंह बाये खड़ी हो गयीं।

यह परियोजना लगाने पर बिड़ला को मोदी द्वारा लंदन की कोर्टोल्ड्स कंपनी से खरीदे जाने-वाले कथित पुराने (सैकेंड हैंड) संयंत्र को लेकर एतराज है। बिड़ला के निकटस्थ सूत्र सवाल के अंदाज में पूछते हैं, "उनकी कंपनी ग्रेसिम ऐसे कारखानों के लिए जब आधुनिकतम संयंत्र, मशीननरी और तकनीकी सेवा कोरिया, थाइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देशों को दे चुकी है, तो मोदी को कोर्टोल्ड्स से ४८ साल पुराने संयंत्र के आयात की इजाजत क्यों दी जाये ?" जबकि मोदी ने केन्द्र सरकार को भेजे गये अपने ज्ञापन में कहा है "मेरी प्रस्तावित परियोजना से वी० एस०एफ० के क्षेत्र में पिछले ४० वर्षों से ग्रेसिम का चल रहा एकाधिकार टूटने और कड़ी होड़ पैदा होने का डर है, जिस कारण बिड़ला विरोध कर रहे हैं।" मगर बिड़ला ने कहा है, "उनकी कंपनी एकाधिकारवाद में कतई विश्वास नहीं रखती। ग्रेसिम ने तो उसकी प्रतिस्पर्धियों में से एक कंपनी साउथ इंडिया विस्कोस को वी०एस०एफ० संयंत्र पुनः चालू कराने में मदद की। उसका यह संयंत्र बंद हो गया था, लेकिन ग्रेसिम के सहयोग की बदौलत उसमें प्रतिदिन २० टन फाइबर का उत्पादन पुनः शुरू हुआ।" बिड़ला के निकटस्थ सूत्र पूछते हैं, "यदि ग्रेसिम को प्रतिस्पर्धा का डर सताता, तो वह अपनी इस प्रतिस्पर्धी कंपनी का संयंत्र पुनः चालू करवाने में मदद क्यों करती ? हालांकि साउथ इंडिया विस्कोस का कारखाना अब फिर बंद हो गया है। इस क्षेत्र में कर्नाटक की तुंगभद्रा

आदित्य विक्रम बिड़ला

कंपनी एकाधिकारवाद में कतई विश्वास नहीं रखती। ग्रेसिम ने तो उसकी प्रतिस्पर्धियों में से एक कंपनी साउथ इंडिया विस्कोस को वी० एस०एफ० संयंत्र पुनः चालू कराने में मदद दी।

फाइबर्स भी है, जिसका कारखाना भी बंद पड़ा है। ये दोनों कंपनियां छोटी हैं और प्रतिस्पर्धा के लिहाज से उल्लेखनीय नहीं। यों देश में इस किस्म का फाइबर बनाने के लिए सरकार ने पिछले दस सालों में कुल सात आशय पत्र जारी किये हैं।

बिड़ला का वर्चस्व : सच है कि वी०एस०एफ० के क्षेत्र में बिड़ला का वर्चस्व रहा है। इस उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय कीमत की तुलना में ग्रेसिम के दाम काफी ऊंचे हैं। फिर भी वह भारी मुनाफा अर्जित करती रही है, क्योंकि भारत में इस उत्पाद की मांग सप्लाई से काफी ज्यादा है और ग्रेसिम एकमात्र सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। योजना आयोग के अनुसार देश में १९८९-९० में सालाना १.८० लाख टन वी०एस०एफ० की मांग होगी, जबकि ग्रेसिम ८० हजार टन माल का उत्पादन कर रही है। मौजूदा अधिक मांग की तरह बाद में भी काफी माल का आयात जारी रहेगा। (हालांकि वी०एस०एफ० की मांग के बारे में योजना आयोग के उक्त अनुमान में 'नोव वुवन' उद्योग की जरूरतों को शामिल नहीं किया गया है) बहरहाल, मोदी ५२,५०० टन सालाना क्षमतावाला कारखाना लगाना चाहता हैं, जिसकी इजाजत देने पर कुल वार्षिक उत्पादन बढ़कर १.३२ लाख टन हो जायेगा।

बिड़ला के प्रवक्ता का कहना है कि ग्रेसिम के कारखाने की क्षमता बढ़ायी जा सकती है, जिस कारण विदेशी सहयोग की जरूरत ही नहीं है। यदि मोदी को कारखाना लगाने की इजाजत देना ही है, तो ग्रेसिम, कोर्टोल्ड्स से श्रेष्ठ एवं आधुनिक संयंत्र देने में सक्षम है। मोदी इसके विरोध में कहते हैं कि बिड़ला का कारखाना ४० वर्ष पुराना है और इस दौरान उसकी टैक्नोलाजी को आधुनिक नहीं बनाया गया। मोदी का यह भी दावा है कि वह अपने आयातित कारखाने से ग्रेसिम की तुलना में विशेष किस्म का ४० प्रतिशत अधिक मजबूत वी०एस०एफ० बनायेंगे। मगर बिड़ला के निकटस्थ सूत्र गर्व के साथ बताते हैं, "ग्रेसिम अपनी उत्तम टैक्नोलाजी के बूते पर कोर्टोल्ड्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी पीछे छोड़ चुकी है। क्यूबा की सरकारी कंपनी यरेयोनोरा ने कोर्टोल्ड्स का प्रस्ताव नामंजूर कर, ग्रेसिम को चुना और उसने अपने वी०एस०एफ० संयंत्र की पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चर), पुनर्नवीनीकरण (रिनोवेट) और आधुनिकीकरण में मदद ली। इन सूत्रों का प्रश्न है, "विदेशी भूमि पर जो कोर्टोल्ड्स ग्रेसिम से पिछड़ गयी, क्या भारतीय भूमि पर उसे बेवजह आमंत्रित कर स्वदेशी कंपनी को नीचा दिखाने की इजाजत दी जानी चाहिए ?"

मोदी फाइबर्स लि० के एक प्रवक्ता का कहना था, "किसी भी उद्योग में व्यावसायिक प्रतियोगिता से कंपनियों में अच्छे-से-अच्छे उत्पाद बनाने की होड़ का मार्ग प्रशस्त होता है और उत्तम क्वालिटी का माल जनता को सुलभ होता है। इससे उत्पादन विक्री में वृद्धि होती है। एस०के० मोदी का सपना है, कि वह देश में ऐसा विशेष किस्म का मानव-निर्मित वी०एस०एफ० बनाये, जिसके निर्यात से भारत को विश्व के मानचित्र में काफी ऊंचे स्थान पर रखा जा सके।

प्रवक्ता का यह भी कहना था, "प्रधानमंत्री देश को २१वीं सदी में ले जाने के प्रति कटिबद्ध नजर आते हैं। इसके लिए सरकारी फैसले शीघ्र और वस्तुनिष्ठ तरीकों से लिए जाने चाहिए और एकाधिकारवादी घरानों के बेवजह दबाव-विरोध को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। मोदी की परियोजना संबंधी पेशकश पर भी फैसला लेने में उन्हीं बातों का खयाल रखा जाना चाहिए।"

मोदी ने कहा है कि ग्रेसिम द्वारा विदेशों में संयंत्र और मशीनरी लगाने में मदद देने का दावा खोखला साबित हो गया है। उनका तर्क है, "ग्रेसिम ने आज तक ये सभी चीजें पूरी तरह सिर्फ अपने बूते पर कहीं भी नहीं लगायी। क्यूबा में उसने संयंत्र व मशीनरी की मात्र मरम्मत-सफाई का काम किया है। इंडोनेशिया, थाइलैंड में लगाये संयंत्र ग्रेसिम के संयुक्त उद्यम (जोइंट वेंचर) हैं। उन्हें लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई टेंडर नहीं मांगे गये। तिस पर ये दोनों संयंत्र कुछ वर्षों से बंद पड़े हैं। दक्षिण कोरिया में ग्रेसिम ने संयंत्र और मशीनरी लगाने का दावा किया है, लेकिन यह कारखाना संतोषजनक ढंग से कभी चला ही नहीं, वह संयंत्र १९८० में शुरू हुआ और १९८२ में उत्पादन बंद हो गया।

मोदी की परियोजना से देश को १० साल में ५ अरब रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, क्योंकि परियोजना में उसके २५ प्रतिशत उत्पाद के निर्यात की शर्त है। इससे देश को वी०एस०एफ० का आयात कम करना पड़ेगा, साथ ही मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी हाथ लगेगी।

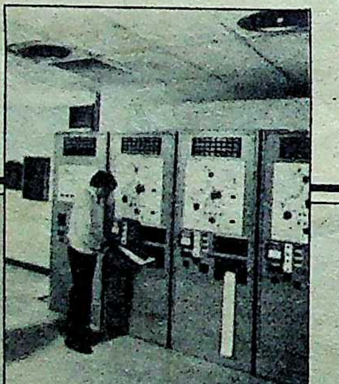

मेरी प्रस्तावित परियोजना से वी०एस०एफ० के क्षेत्र में पिछले ४० वर्षों से ग्रेसिम का चल रहा एकाधिकार टूटने और कड़ी होड़ पैदा होने का डर है, जिस कारण बिड़ला विरोध कर रहे हैं।

एस०के० मोदी

मोदी और बिड़ला द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ, प्रस्तुत इन तर्कों के कारण केन्द्र सरकार लंबे समय तक कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पायी। अन्ततः जून १९८७ में केन्द्र सरकार के उच्च स्तरीय 'परियोजना मंजूरी बोर्ड' ने मोदी को अपनी परियोजना के सिलसिले में आधुनिकतम टैक्नोलाजी पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेंडर आमंत्रित करने का निर्देश दिया। मोदी से कहा गया कि इसमें वह स्वदेशी वी०एस०एफ० सप्लाइकर्ता (स्पष्ट है—ग्रेसिम) को भी आमंत्रित करें। मोदी जापान की मास्बेनि कार्पोरेशन, स्विट्जरलैंड की मोरेर एस०ए० अमरीका की डू पोंट और आस्ट्रिया की लेन्झिंग नामक कंपनियों से इस बारे में संभावनाएं टटोल रहे हैं।

मोदी की जिद्द : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेंडर जारी करने और उसमें भारतीय कंपनी को भी शामिल करने के नये निर्देश के बावजूद मोदी कह रहे हैं कि वह ग्रेसिम से किसी भी हालत में संयंत्र नहीं खरीदेंगे। यदि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया, तो वह इस परियोजना को ही छोड़ देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो वी०एस०एफ० परियोजना विवाद जरूर समाप्त हो जायेगा, लेकिन क्या मोदी-बिड़ला में कटुता पर भी विराम चिह्न लग जायेगा ?

इस मोदी-बिड़ला द्वंद्व में पुरानी खानदानी और नव-धनाढ्य उद्योगपतियों का संघर्ष भी झलकता है। दो वर्ष पहले भारतीय उद्योगपतियों की बिरादरी के नेतृत्व को लेकर 'फिक्की' में बिड़ला-मोदी गुटों में खासी ठनी थी। बिड़ला बंधुओं का आरोप था कि मोदियों ने अपने कठपुतलों को बेनामी सदस्य बना, संस्था को खोखला किया था। बिड़ला परिवार स्वाधीनता संग्राम के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है और यह बात नकारी नहीं जा सकती कि वह कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर आर्थिक विकास का अगुआ रहा है। सर्वोच्च सरकारी तबकों में उसकी अच्छी पहुंच है। उसके प्रतिस्पर्धियों को लगता है कि इसी से वह अपना एकाधिकारी वर्चस्व स्थापित करने में सफल होते रहे हैं।

पूंजीवादी तबके में आपसी गलाकाट प्रतिद्वंद्विता कोई नयी चीज नहीं। कुछ दिन पहले पुराने-नये' पैसे के टकराने की झलक बोम्बे डाइंग के स्वामी नसली वाडिया और नयी-सतह से उठे उद्यमी धीरूभाई अंबानी की रस्साकशी में भी देखने को मिली थी। वह लड़ाई भी पोलियेस्टर नामक मानव-निर्मित रेशे के उत्पादन की दो भिन्न प्रणालियों के बहाने लड़ी गयी थी। असली मुद्दा वही था जो अब है—लाभप्रद क्षेत्र में किसी दूसरे प्रतिद्वंद्वी को आने-उभरने से रोकना। यह तो समय ही बतलायेगा कि बिड़ला-मोदी की यह मुठभेड़ इन दोनों में से किसके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होती है।

—विशेष प्रतिनिधि

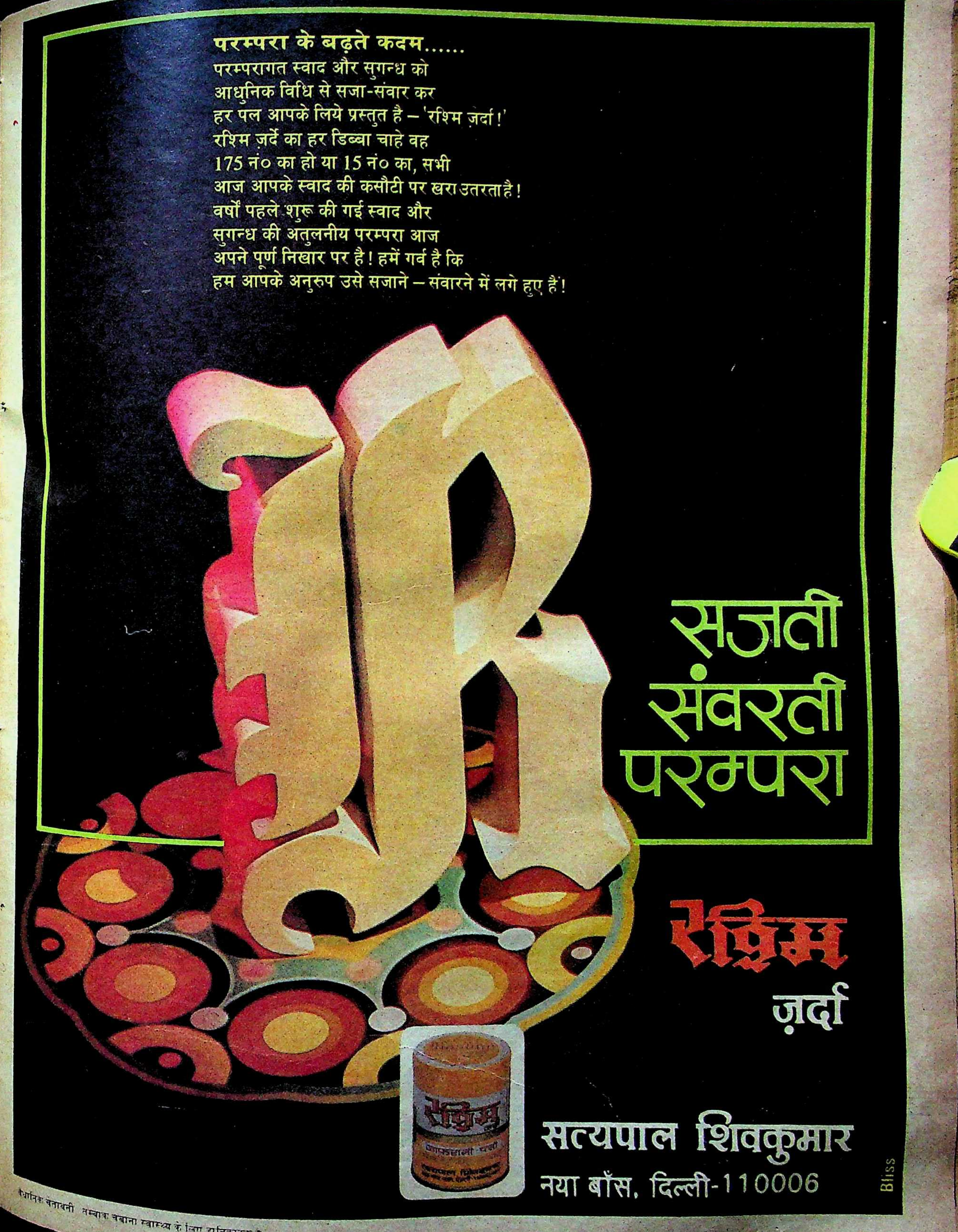

परम्परा के बढ़ते कदम......

परम्परागत स्वाद और सुगन्ध को
आधुनिक विधि से सजा-संवार कर
हर पल आपके लिये प्रस्तुत है – 'रश्मि ज़र्दा!'
रश्मि ज़र्दे का हर डिब्बा चाहे वह
175 नं० का हो या 15 नं० का, सभी
आज आपके स्वाद की कसौटी पर खरा उतरता है!
वर्षों पहले शुरू की गई स्वाद और
सुगन्ध की अतुलनीय परम्परा आज
अपने पूर्ण निखार पर है! हमें गर्व है कि
हम आपके अनुरुप उसे सजाने – संवारने में लगे हुए हैं!

सजती
संवरती
परम्परा

रश्मि
ज़र्दा

सत्यपाल शिवकुमार
नया बाँस, दिल्ली-110006

Bliss

वैधानिक चेतावनी तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

माधुरी दीक्षित छाया : दुर्गा प्रसाद

माधुरी दीक्षित की हाय

सुभाष घई ने २५ लाख रुपए खर्च करके इस सदी का सबसे शानदार मुहूर्त फिल्म 'देवा' का किया था। पर, अब चार दिन शूटिंग करने के बाद सुभाष घई ने इस फिल्म के निर्माण को ही नहीं रोक दिया है, बल्कि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को अलग भी कर दिया है। 'विधाता', 'कर्मा' के पृष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार के खुदगर्जी की खुलेआम निंदा करने के बाद यही सुभाष घई अब 'देवा' की कहानी में उलटफेर करके दिलीप कुमार के पास 'देवा' का उद्धार करवाने के लिए पहुंच गये हैं। इसमें सहभागी होंगे, अनिल कपूर और जैकी श्राफ। 'देवा'-प्रकरण के बाद अमिताभ बच्चन जहां मौन हैं, वहीं सुभाष घई कहते फिर रहे हैं कि अमिताभ ने ८ घंटों के १५० शूटिंग डेट्स देने का वादा किया था, लेकिन बाद में ८ घंटे से घटाकर चार घंटे कर दिये। इससे ३५० से अधिक दिन तक अमिताभ को शूटिंग करनी पड़ती और 'देवा' का बजट ढाई करोड़ रुपए से छह करोड़ रुपए एवं निर्माण अवधि डेढ़ वर्ष के बजाय चार वर्ष तक पहुंच जाती। ऐसे में इतनी मंहगी फिल्म को भला कौन हाथ लगाता। 'देवा' बंद करने से कौन दुखी है और कौन कितना प्रसन्न, यह हिसाब लगाना मुश्किल है, पर 'देवा' बंद होने से सबसे अधिक खुश है, माधुरी दीक्षित। सुभाष घई कभी माधुरी दीक्षित के गाड फादर कहे जाते थे, लेकिन 'कर्मा' में जब घई ने माधुरी दीक्षित को हीरोइन की जगह एक्स्ट्रा बनाकर रख दिया, तो माधुरी दीक्षित अपने इस गाड फादर से भड़क गयी और अब, जब 'देवा' बंद होने की खबर उसे मिली तो उसने कहा, ''मेरी हाय कहां जायेगी?''

आठवें दशक के गुरुदत्त की मेनका!

बाबू हवेलीराम ने 'बुनियाद' में जवान से बूढ़े की भूमिका निभा कर अभिनय के झंडे क्या गाड़े कि एक तरफ लोग उन्हें आठवें दशक का गुरुदत्त कहने लगे, तो दूसरी तरफ वह कभी 'कामाग्नि' जैसी फिल्म में, तो कभी 'कच्ची कली' जैसी उत्तेजक सेक्स-प्रधान फिल्म में दिखलायी पड़ने लगे। टीना मुनीम ने उनके साथ 'कामाग्नि' के बाद जोड़ी बनाने से किनारा कस लिया है, लेकिन 'कच्ची कली' की नायिका सोनिका गिल इसके लिए तैयार है और इस तरह की फिल्में बनाने के लिए दक्षिण के कई निर्माता आतुर भी हैं। यद्यपि उनकी 'बुनियाद'-धर्मपत्नी लाजोजी (अनीता कंवर) उनके साथ कई फिल्मों में काम कर रही है, लेकिन दोनों की जोड़ी रोमांटिक कम, अधेड़ स्त्री-पुरुष की ज्यादा लगती है, इसीलिए सुहागरात के दृश्य में भी वे युवा नवविवाहित कम तीसरा-चौथा विवाह करनेवाले अधेड़ विवाहित ज्यादा लगते हैं। ग्लैमरस चित्र खिंचवा कर रोमांटिक भूमिकाएं हासिल करने में असफल अनीता कंवर ने जब डकैत भूमिकाओं वाली फिल्में लेनी शुरू कर दिया है तो बेचारे आलोक नाथ को 'कामाग्नि' या 'कच्ची कली' जैसी फिल्में लेने में क्यों संकोच होता? उनके पास पिछले दिनों दक्षिण का एक फिल्म निर्माता 'काम शास्त्र' जैसी एक फिल्म 'कलियुग की मेनका' का आफर लेकर पहुंचा तो उन्होंने पूछा, ''मेनका कौन होगी?'' उसने जवाब दिया, ''वही 'कच्ची कली' वाली सोनिका!'' तब पता नहीं, आलोक नाथ ने क्या जवाब दिया, लेकिन लगता है दक्षिण के सेक्स फिल्में बनाने वाले निर्माता आलोकनाथ के आठवें दशक का गुरुदत्त बनने का सपना जरूर चूर-चूर कर देंगे।

संगीता का कड़वा घूंट

माडल से फिल्म अभिनेत्री बनी संगीता बिजलानी की नाराजगी की बिजली कौंध रही है, अपने तथाकथित गाड फादर जे०पी० दत्ता पर, जो 'हत्यारे' के अनुबंध में उन्हें जकड़ कर खुद तो फिल्मों पर फिल्म साइन करते जा रहे हैं और अनुबंध की शर्तों के मुताबिक वह एक-के-बाद-एक फिल्मों के आफर

सोनिका गिल

छाया : डी०आर० यादव

संगीता बिजलानी

छाया : तैयब बादशाह

खोती जा रही है। 'हत्यारे' से डिंपल कपाड़िया के रहस्यमय ढंग से अलग हो जाने पर जे०पी० दत्ता ने संगीता बिजलानी को फिल्म में लिया, तो बड़ी खुशी से उसने तीन वर्ष के अनुबंध पर दस्तखत कर दिये। शर्तों के मुताबिक वह न तो फिल्मी मुहूर्तों में जा सकती है, न ही फिल्मी पार्टियों या फिल्म निर्माताओं के घर पर।

"जे०पी० जैसे निर्देशक के साथ मैं तीन क्या तीस वर्षों का कांट्रैक्ट साइन कर सकती हूं, लेकिन फिल्में बनें तो सही। न हत्यारे रिलीज होगी और न ही मुझे दूसरी फिल्मों में काम मिलेगा। जे०पी० ने वादा किया था कि 'उनकी हर फिल्म में मैं हीरोइन होऊंगी' कहनेवाली संगीता को सच का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। जिस डिंपल ने जे०पी० से झगडा कर 'हत्यारे' छोड़ दिया था, उसी ने जे०पी० से दोस्ती कर उनकी नयी फिल्म 'बटवारा' हथिया ली और दूसरी तरफ संगीता को एक छोटी-सी फिल्म पार्टी में चले जाने पर फिल्म निर्माता की खूब लताड़ मिली।

अब संगीता का यह दुर्भाग्य कि 'हत्यारे' फिल्म के दोनों नायकों (ऋषि कपूर एवं शत्रुघ्न सिन्हा) के झगड़ों के कारण फिल्म डिब्बे में बंद पड़ी रही। दोनों अभिनेता फिल्म के टाइटल में एक-दूसरे को अपने से जूनियर घोषित करते हुए अपना नाम पहले रखने की जिद्द पर अड़े रहे। चिंटू का कहना था कि जब उसकी पहली फिल्म 'बाबी' हिट हुई, तो उस समय शत्रु खलनायक की छोटी-मोटी भूमिकाएं निभा रहे थे। शत्रु की दलील थी कि जब वह फिल्मों में आये तो चिंटू चाइल्ड आर्टिस्ट (मेरा नाम जोकर) था। खैर, अब इस झगड़े को खुद शत्रु ने खतम कर दिया, फिल्म से निकल कर, लेकिन संगीता की समस्या तो अब भी बनी हुई है कि फिल्म कब पूरी हो और उसे इस कैद से मुक्ति मिले।

दोस्ती की कीमत

राजेश खन्ना की दूसरी वापसी और पूनम की स्टारडम एक ही फिल्म से हुई थी- 'द रोज'। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन 'द रोज' देखकर फिल्म निर्माताओं ने दोनों के घर चक्कर लगाने शुरू कर दिये थे। 'द रोज' ने ही राजेश खन्ना के लिए दक्षिण फिल्म निर्माताओं के द्वार कुछ इस तरह खोल दिये कि वह तमिल, तेलुगु, मलयालम के सुपर हिट फिल्मों को हिन्दी में रीमेक करने में कुछ इस ढंग से मशगूल हुए कि बंबई का रास्ता ही भूल गये।

एक दिन राजेश खन्ना खुफिया खबर मिलते ही रात ढाई बजे जेम्स बांड की तरह डिंपल को रंगे हाथ पकड़ने बंबई आ धमके। यहीं से शुरू हुई राजेश-डिंपल के अलगाव की अकथ कथा। 'द रोज' के समय पूनम ढिल्लो डिंपल की हम निवाला सहेली थी, लेकिन उक्त कांड के बाद उसने पूनम का मुंह भी न देखने की कसम खा ली। डिंपल को शक था कि बंबई में बैठकर वही राजेश खन्ना को उसके बारे में हर खुफिया खबर दे रही थी और उसी ने सौतन टीना मुनीम का परिचय राजेश से करवाया था।

टीना भी पूनम की हम निवाला सहेली बन गयी थी, राजेश के संपर्क में आकर, लेकिन अब वह भी सख्त खफा है, पूनम पर। उसे भी डिंपल की तरह शक था कि उसकी और अनिल अंबानी के अफेयर की खुफिया खबर पूनम ने ही राजेश को दी थी, इसलिए टीना ने भी आइंदा पूनम की शक्ल न देखने की कसम खा ली थी। दोनों की रंजिश 'हब्बा खातून' के निर्देशक मुजफ्फर अली के लिए सिर-दर्द बन गयी है। उन्होंने डिंपल के कहने पर राजबब्बर को, राजेश खन्ना के साथ बढ़ती दोस्ती के कारण निकाल कर विनोद खन्ना को ले लिया तो पूनम भी डरी कि कहीं अब उसकी पारी न हो, लेकिन यहां उसकी मदद को राजेश खन्ना आगे आ गये कि अगर पूनम को भी निकाला गया तो वह पूनम और राजबब्बर को लेकर एक नया 'हब्बा खातून' बना देंगे।

शायद मुजफ्फर अली को दोस्ती का अर्थ समझ में आ गया होगा, ऐसा लखनऊवाले आज भी सोचते हैं।

पूनम ढिल्लो, शफी इनामदार एवं राजेश खन्ना 'अवाम' में

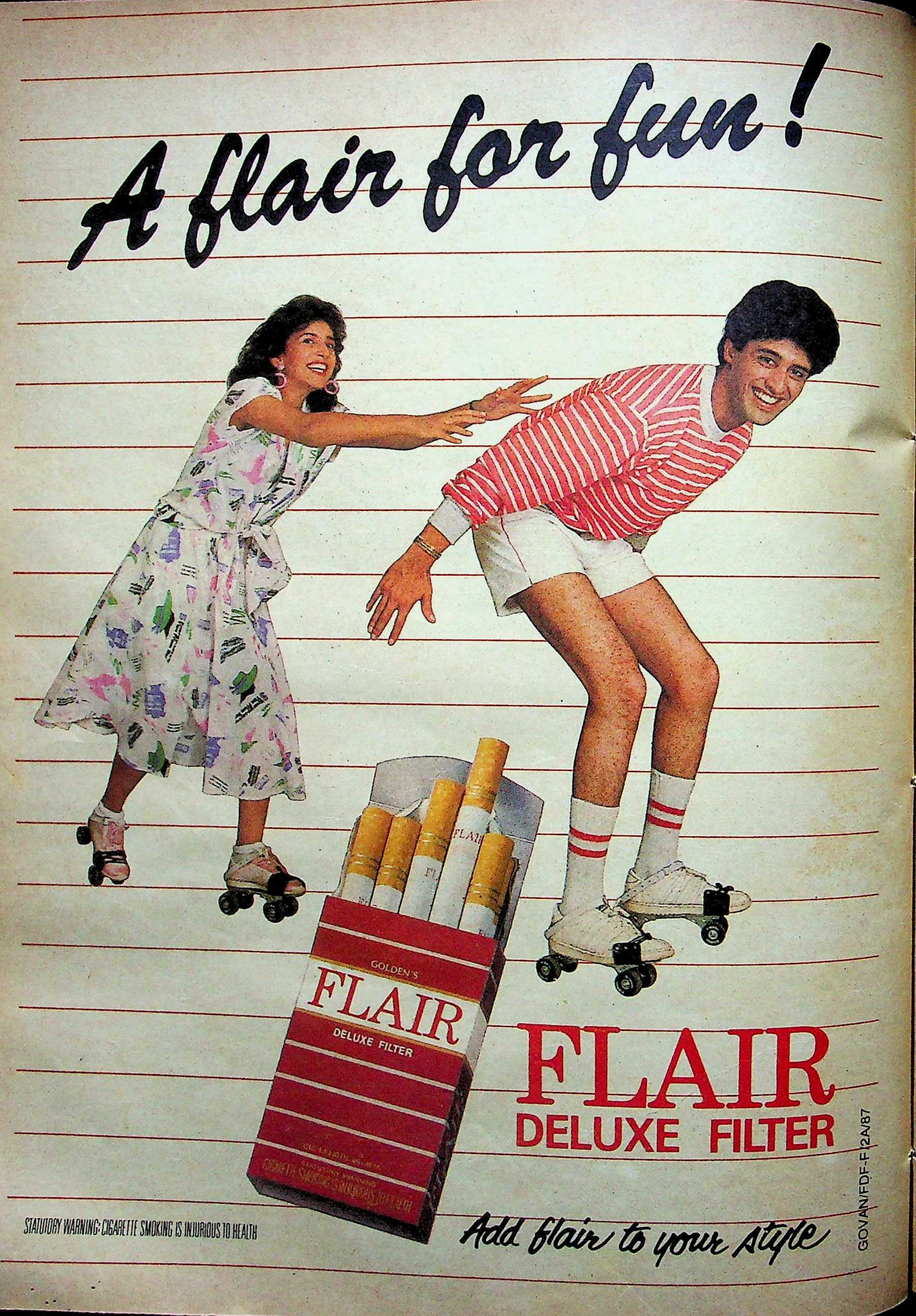
A flair for fun!
GOLDEN'S
FLAIR
DELUXE FILTER
FLAIR
DELUXE FILTER
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
Add flair to your style
GOVAN/FDF-F12A/87

धीरज कुमार

मंडी हाउस में पहुंच का फल

लगभग डेढ़ दशक पहले 'रातों का राजा' फिल्म से फिल्म कैरियर शुरू करने वाले धीरज कुमार डेढ़ दशक की गुमनामी के बाद इन दिनों मंडी हाउस की कृपा से दूरदर्शन पर छाये हुए हैं। जहां बड़े-बड़े निर्माताओं के टी०वी० सीरियल को दूरदर्शन पर स्थान नहीं मिल पा रहा है, लोकप्रिय सीरियलों को 'एक्सटेंशन' नहीं मिल पा रहा है, वहीं धीरज कुमार के ऊबाऊ और स्तरहीन सीरियल एक-के बाद-एक दूरदर्शन पर दिखाये ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें 'एक्सटेंशन' मिलने की संभावनाएं भी हैं। मंडी हाउस में धीरज कुमार की पैठ का राज क्या है ?

धीरज कुमार, जूबी कोछड़ और लता मंगेशकर 'अदालत' की रिकार्डिंग के समय

फिल्म अभिनेता धीरज के साथ अगर उनकी उपलब्धियों (अभिनय संबंधी) की गणना की जाये, तो उनके हिस्से में शून्य ही आयेगा। लगभग डेढ़ दशक पहले 'जीरो हीरो' कह कर जिस फिल्म उद्योग ने धीरज को हकाल दिया था, उसी धीरज के पास आजकल उन्हीं हकाल देनेवाले फिल्मकारों के टेलीफोन-कालों की भरमार रहती है।

फोन करनेवाले लोग उन्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि धीरज के पास आने वाले ये फोन उनके दिल्ली और मंडी हाउस-संपर्कों के कारण हैं। हर कोई धीरज के 'दिल्ली कनेक्शन' को भुनाकर अपने सीरियल मंडी हाउस (दूरदर्शन महानिदेशालय) से पास करा लेना चाहता है।

धीरज का दिल्ली-संपर्क अगर बहुत प्रभावशाली नहीं होता, तो जब दूसरे प्रख्यात सीरियल-निर्माता अपने लोकप्रिय सीरियलों के एक्सटेंशन के लिए मंडी हाउस के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे, धीरज बड़ी शान से एक ही झटके में 'कहां गये वो लोग' जैसे बचकाने एवं स्तरहीन सीरियल का एक्सटेंशन आर्डर मंडी हाउस से पाने में सफल हो गये थे। यह उनके संपर्कों का ही प्रताप था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 'कहां गये वो लोग' को १९८६ के सर्वश्रेष्ठ सीरियल के पुरस्कार के लिए ही नहीं चुना, बल्कि उन्हें एक और स्तरहीन टी०वी० सीरियल 'अदालत' बनाने की अनुमति भी दे दी। (संभव है, यह सीरियल भी १९८७ का सर्वश्रेष्ठ सीरियल का पुरस्कार झटक ले जाये।)

यह भी महज इत्तफाक है कि शुरुआत में 'दिल्ली सोर्स' के लिए उन्होंने जिस भारत कुमार (मनोज कुमार) की बैसाखी थामी थी, उसी भारत कुमार को अब अपने सीरियल को पास कराने के लिए धीरज कुमार के दिल्ली-संपर्क की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरज कुमार ने 'कहां गये वो लोग' की शुरुआती-कमेंट्री की जिम्मेदारी के लिए मनोज कुमार को चुना था।

यों धीरज कुमार अपने दिल्ली-संपर्क की बात को सिर्फ 'दोस्ती' बतलाते हैं। उनका कहना है, "मंडी हाउस वालों ने मेरे तीनों सीरियलों ('कहां गये वो लोग', 'अदालत' एवं 'जान आफत में') की स्क्रिप्ट को भली प्रकार जांचा-परखा था, फिर उसके पायलट देखे थे। मेरे सीरियल अगर प्रभावशाली एवं प्रेरक नहीं होते तो वे भला उन्हें क्यों चुनते। मुझसे, बड़े-बड़े संपर्क-सूत्र एवं प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी अपने सीरियलों के लिए दरख्वास्तें दे रखी थीं, लेकिन उनमें दम नहीं था, इसीलिए उन्होंने उनके सीरियलों को नापास कर दिया।"

'कहां गये वो लोग' की कमजोरियों की जिम्मेदारी धीरज उसके निर्देशक पर डाल देते हैं, क्योंकि वह इस सीरियल के मात्र निर्माता थे। इस बार 'अदालत' और 'जान आफत में' का निर्देशन वह खुद कर रहे हैं, निर्मात्री हैं, उनकी पत्नी जूबी कोछड़। 'अदालत' के साथ-साथ वह ब्रेकफास्ट टी०वी० के लिए 'जान आफत में' की भी शूटिंग कर रहे हैं। इसे शीघ्र ही 'धमाल' के बाद १३ एपीसोडों में दिखलाया जायेगा और धीरज को पूरा विश्वास है कि मंडी हाउस से उनके दोनों सीरियलों को एक्सटेंशन मिल जायेगा।

"हमने काफी पहले 'जान आफत में' की रूपरेखा मंडी हाउस को दी थी" धीरज ने 'माया' को बतलाया, "लेकिन इसका क्लीयरेंस थोड़ा विलंब से मिला। हमने १९ एपीसोडों की रूपरेखा दी थी, लेकिन १३ की ही स्वीकृति मिली। 'अदालत' और

'जान आफत में' सीरियल में राजेंद्रनाथ और सईद जाफरी

'जान आफत में' प्रेरक एवं मनोरंजक सीरियल हैं, जो मनोरंजन के साथ नैतिक आदर्श एवं निष्ठा की प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए हमें पूरी आशा है कि दोनों सीरियलों को १३ और एपीसोड दिखाने की अनुमति मिल जायेगी। दोनों सीरियलों के कथानक का कैनवास इतना बड़ा है कि इन्हें हम दो वर्ष तक चला सकते हैं और दर्शकों को उनसे ऊब भी नहीं होगी।''

लेकिन धीरज को संभवतः 'अदालत' सीरियल से होने वाली दर्शकों की बोरियत का पता नहीं, इसीलिए वह न तो अदालत के अगले एपीसोडों में परिवर्तन कर उसमें रोचकता, यथार्थता एवं विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं और न ही 'जान आफत में' को 'स्लैपिस्टिक' फिल्मी मसालोंवाली कामेडी की शैली से अलग कर पा रहे हैं।

'अदालत' का सबसे कमजोर पक्ष है, शिथिल निर्देशन एवं बिखरी हुई पटकथा। हर एपीसोड में प्रमुख भूमिका अभिनीत करने के शौक ने उन्हें दूसरे पक्षों पर ध्यान देने तथा साथ ही खुद के किरदार को और भी प्रभावशाली बनाने का मौका ही नहीं दिया। निर्देशन और अभिनय के बीच बहुत फासला होता है और कलाकार-निर्देशक कैमरे के पीछे या सामने होता है तो अपने एक अस्तित्व को भूलकर कुछ समय के लिए वह वही बन जाता है, जो कर रहा होता है। धीरज मनोज कुमार को अपना पथ-प्रदर्शक मानते हैं, इसीलिए फ्रेम में ज्यादा-से-ज्यादा खुद को फोकस में रखने की कोशिश करते हैं और संवाद बोलते समय लक्ष्य बिंदु की ओर देखने के बजाय कैमरे की लेंस में इस तरह देखते हैं जैसे आइने के सामने खुद का अक्श देख रहे हों। ऐसे में उनका सारा 'कंसंट्रेशन' अपने किरदार के बजाय खुद को 'एक्सपोज' करने पर चला जाता है, इसीलिए उनका हर एपीसोड सतही मेलोड्रामा बन कर रह जाता है।

गुजरा जमाना : लगभग डेढ़ दशक पहले धीरज की प्रदर्शित प्रथम फिल्म 'रातों का राजा' चवन्नियां दर्शकों को बहुत पसंद आयी थी, लेकिन धीरज इस तरह की फिल्मों के निर्माताओं की निगाह में नहीं चढ़ सके। 'बहुरुपिया', 'दीदारं' आदि फिल्में करने के बाद वह एकदम से आउट हो गये। कुछ समय बाद मनोज कुमार ने 'रोटी, कपड़ा और मकान' में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका देकर उन्हें नायक से चरित्र अभिनेता बना दिया। इसे धीरज ने नियति का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन नायकों द्वारा खुद एंटी रोल स्वीकार कर लिये जाने तथा कादर खान, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर द्वारा छोटे बजट की फिल्मों में चरित्र अभिनेताओं की छोटी-छोटी भूमिकाएं भी हथिया लेने की प्रवृत्ति के कारण धीरज कुमार जैसे कलाकारों के सामने काम का संकट पैदा हो गया।

धीरज ने खाली समय में माडलिंग भी की, लेकिन सीरियलों का जमाना शुरू होने पर वह अचानक व्यस्त हो उठे और बंबई दिल्ली की यात्रा उनके लिए अंधेरी-चर्चगेट की यात्रा के समान बन गयी और देखते-देखते वह सर्वाधिक व्यस्त निर्माता-निर्देशक बन बैठे। अब उनके पास खुद की

साक्षात्कार/धीरज कुमार

मेरा काम ही बतायेगा कि मैं छोटा हूं या बड़ा

माया : आपकी फिल्मी और टी०वी० शुरुआत कुछ गलत ढंग से हुई। न तो आपको अपनी पहली फिल्म 'रातों का राजा' में अभिनय की प्रशंसा मिली, न ही टी०वी० सीरियल 'कहां गये वो लोग' में?

धीरज : आपको गलत खबर मिली है। 'रातों का राजा' बाक्स आफिस पर हिट हुई थी और 'कहां गये वो लोग' को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सीरियल मान कर पुरस्कृत किया है। बंबई की एक संस्था ने भी यही पुरस्कार देकर इसे सम्मानित किया है। लोगों ने इस सीरियल को काफी पसंद किया, इसकी तारीफ के पत्र मुझे अब भी मिलते रहते हैं। अब मेरा नया सीरियल 'अदालत' दूरदर्शन पर दिखलाया जा रहा है। इससे लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरी शुरुआत काफी अच्छी हुई थी—फिल्मों में भी, टी०वी० में भी।

माया : लेकिन समीक्षकों ने दोनों बार आपकी तारीफ नहीं की?

धीरज : यह उनकी अपनी बात है। मैं यह जानता हूं कि मैंने पूरी मेहनत की, अपने किरदार को ठीक ढंग से जीने के लिए पूरा प्रयास किया और आम दर्शक ने सराहा। बस, यही मेरे लिए काफी है।

माया : लेकिन आम दर्शक भी आपकी तुलना श्रेष्ठ सीरियल निर्माताओं से नही करते।

धीरज : क्या आप किसी व्यक्ति से तुलना करना ही उसकी श्रेष्ठता समझते हैं? मैं अपनी तुलना किसी से भी नहीं करना या करवाया जाना पसंद करता। मैं धीरज कुमार हूं, धीरज कुमार ही बना रहना चाहता हूं। मेरी खुद की अपनी 'आइडेंटिटी' है और उस 'आइडेंटिटी' को बरकरार रखना चाहता हूं।

माया : अभी आपने कहा कि आप की पहली फिल्म 'रातों का राजा' बाक्स आफिस पर हिट हुई थी, फिर आप अचानक गुम कैसे हो गये?

धीरज : मैं तो इसे मुकद्दर की बात कहूंगा, लेकिन कुछ और बातें भी थीं, जिसे स्वीकार करने में अब कोई हर्ज नहीं है। उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी 'टैक्टिस' से अनजान था कि स्टार बनने के लिए बहुत से दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं।

माया : मसलन?

धीरज : यहां जीरो पावर के बल्व को भी हजार पावर के बल्व का अहसास करा देने पर ही सफलता मिलती है। स्टार बनने के लिए जरूरी होता है, भारी भरकम 'पब्लिसिटी कैंपेन।' बहुत से लोग पब्लिसिटी के लिए न केवल उलटे-सीधे 'स्कैंडल' खुद फैलाते हैं, बल्कि फिल्म मार्केट में अपनी साख बनाने के लिए तरह-तरह के नाटक करते हैं। दूसरों के कैंपों में घुसकर अधिक-से-अधिक फिल्में साइन करने के लिए हरसंभय प्रयास करते हैं। मैंने यह सब कुछ नहीं किया, इसलिए आउट हो गया।

माया : क्या अब आपको फिल्मों में आफर नहीं मिलते, इस कारण टी०वी० सीरियल और फिल्म बनाने की ओर आपका ध्यान गया?

धीरज : कौन कहता है कि फिल्मों में आफर नहीं मिलते। आज भी मुझे बहुत से आफर मिलते हैं, लेकिन जब तक मुझे रोल में कुछ कर दिखाने का अवसर न मिले, तो मैं कैसे स्वीकार करूं उन फिल्मों को। मैंने स्वयं भी दो-तीन फिल्में बनायीं, 'आखिरी चाल' और 'आधी रात के बाद' लेकिन ये फिल्में खास नहीं चलीं। मेरा मन खट्टा हो गया और मैं टी०वी० सीरियल के निर्माण में जुट गया।

माया : आज बड़े-बड़े निर्माता-निर्देशक बी०आर० चोपड़ा ('महाभारत') और रामानंद सागर ('रामायण') टी०वी० सीरियल बना रहे हैं, ऐसे में आप इनके बीच टिक पायेंगे?

धीरज : देखिए, यहां पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान का काम बोलता है। उसका अभिनय और निर्देशन बोलता है। यह तो मेरा काम ही बतायेगा कि मैं छोटा हूं या बड़ा। और भई, 'कहां गये वो लोग' ने यह सिद्ध भी कर दिया है, पुरस्कार जीतकर। इतने सारे सीरियल बने, लेकिन बड़े-बड़े दिग्गजों के सीरियल भी बने, लेकिन श्रेष्ठता का पुरस्कार सिर्फ 'कहां गये वो लोग' को ही मिला।

प्रस्तुति : महादेव शर्मा

यूनिट है, टी०वी० शूटिंग के उपकरण हैं और ढेर सारे सीरियलों तथा टेलीफिल्मों की निर्माण योजनाएं भी। फिल्मों में अभिनय की बात चलने पर वह कहते हैं, "फिल्मों में ऐक्टिंग करने का मौका ही अब कहां है मेरे पास? अब तो जब बहुत अच्छा रोल और बड़ा बैनर मिलेगा, तभी काम करूंगा। वैसे भी मुझे अब फिल्मों से कोई लगाव नहीं रह गया है। बहुत दुख दिया है, इस इंडस्ट्री ने मुझे। अब तो मैं सीरियलों का निर्माण एवं निर्देशन ही करना चाहूंगा।"

धीरज ने 'अदालत' के एक एपीसोड में प्रख्यात गजल एवं भजन गायक अनूप जलोटा से भी अभिनय करवाया है और उन्हें तथा उन जैसे दूसरे क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्तियों को एक-एक कर टी०वी० के छोटे परदे पर लायेंगे ताकि जिनको लोग विभिन्न माध्यमों से सुनते या उनके बारे में सिर्फ पढ़ते रहे हैं, उन्हें अब रूबरू दूरदर्शन पर भी अभिनय करते देख सकें। इस बीच धीरज ने अपने सीरियलों के प्रायोजकों से अच्छा 'रैपर्ट' बना लिया है। उनके लिए वह अब माडलिंग भी करेंगे और जरूरत पड़ी, तो अपनी निर्माण संस्था द्वारा उनके लिए विज्ञापन फिल्म भी तैयार कर दिया करेंगे। उन्होंने अपने एक प्रायोजक, रिचर्डसन हिंदुस्तान, के एक उत्पाद 'एक्शन-५००' के लिए माडलिंग भी की है।

इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक, संभव है, धीरज का हास्य सीरियल 'जान आफत में' दूरदर्शन पर प्रदर्शित होने लगे। नौकर, पागल, मेहमान एवं लाटरी टिकट आदि एपीसोडों की शूटिंग कर वह मंडी हाउस भेज चुके हैं। उनका विश्वास है कि इस हास्य प्रधान सीरियल से उनकी निर्देशन-क्षमता का एक और रूप दिखलायी पड़ेगा। 'जान आफत में' के लिए भी उन्होंने अलग-अलग हास्य लघुकथाएं ली हैं। 'पागल' में केंद्रीय भूमिका राजेंद्र नाथ को दी है, तो 'मेहमान' में सईद जाफरी एवं रोहिणी हटंगणी को। 'करमचंद' में गाजर ने पंकज कपूर को स्टार बना दिया था, अब 'पागल' में यही उपलब्धि गाजर की जगह मूली दिलायेगी हास्य अभिनेता राजेंद्र नाथ को। 'करमचंद-फेम' गाजर की चर्चा चलने पर राजेंद्र नाथ ने बतलाया, "गाजर देर में पचता है, लेकिन मूली भोजन को पचाने के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद तथा कीमत की दृष्टि से सस्ती भी होती है।"

हिंदी फिल्मों एवं सीरियलों का यह दुर्भाग्य रहा है कि फिल्मकारों को हास्य-व्यंग्य की कोई जानकारी ही नहीं रही है। वे हास्य को मसखरापन, भांड़गीरी तथा मुसाहिबाना विदूषकी से अलग कर सोच ही नहीं पाये हैं। परदे पर ऊल-जुलूल हरकतों को ही हास्य का नाम दे दिया गया। हास्य-व्यंग्य की यही नियति शुरू से ही ब्रेक फास्ट टी०वी० के साथ भी जुड़ गयी है। इसीलिए धीरज की 'जान आफत में' 'धमाल' एवं 'उलटा-पुलटा' सीरियलों से कितना बेहतर बन सकेगी, इसे तो दर्शक ही बतायेंगे।

—बंबई ब्यूरो

साक्षात्कार/अनूप जलोटा

सिर्फ शौक के लिए अभिनय

लगभग एक दशक पूर्व लखनऊ तथा आसपास के इलाकों में, अपने तबलची को स्कूटर पर बिठाकर, घूम-घूम कर भजन गाने वाले किशोर अनूप जलोटा दूसरे अनेक 'फिल्मोनियाग्रस्त' युवकों की तरह बंबई हीरो बनने आये थे, लेकिन फिल्म निर्माताओं को उनका मुखड़ा रास नहीं आया तब अनूप जलोटा अपने गीतों के मुखड़ों को भजन और गजल में परिवर्तित कर रंगमंच एवं रिकार्डिंग की दुनिया के ऐसे सितारे बन गये, जिनके कैसेट फिल्मवालों के यहां भी बजने लगे। लेकिन, 'फिल्मोनिया' के रोग से वह अभी भी मुक्त नहीं हो पाये, इसीलिए जब फिल्मवालों ने उन्हें छोटी-मोटी किंतु सम्मानप्रद अतिथि भूमिकाएं देने की पेशकश की, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। 'बुनियाद', 'रामायण', 'कालाजल', 'कहां गये वो लोग' आदि कई टी०वी० सीरियलों के 'टाइटिल सांग' भी गाये। 'कहां गये वो लोग' के निर्माण के दौरान धीरज से उनकी दोस्ती हो गयी और जब धीरज को अनूप जलोटा के अभिनय संबंधी शौक का पता चला तो 'अदालत' के एक एपीसोड में धीरज ने अनूप जलोटा को अभिनय करने का अवसर दिया। आगे की अन्य शृंखलाओं के अलावा 'जान आफत में' भी धीरज अनूप जलोटा से अभिनय करवायेंगे। अनूप जलोटा इस बदलाव से प्रसन्न हैं। प्रस्तुत हैं, उनसे 'माया' की बातचीत के अंश:

माया: तो आप भी सिंगिग स्टार बन रहे हैं?

अनूप: अरे कहां! भाई लोग जब जिद कर देते हैं, तो उनकी फिल्मों में अभिनय भी कर लेता हूं।

माया: तो लोग आपको जबर्दस्ती फिल्म अभिनेता बना रहे हैं? आपको अभिनय का शौक नहीं रहा कभी?

अनूप: रहा, यही शौक तो मुझे बंबई ले आया था।

माया: आप तो अच्छे-भले गीत, गजल और संगीत की दुनिया में रम गये थे, फिर यह शौक कैसे जाग गया, वह भी टी०वी० सीरियलों में?

अनूप: धीरज कुमार हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, उन्होंने आफर दिया, तो मैं मना नहीं कर सका।

माया: गायकी में और अभिनय में क्या फर्क महसूस करते हैं आप?

अनूप: काफी फर्क है। गाना सचाई है और अभिनय नकल है। यद्यपि दोनों के लिए ही तैयारी तो बराबर करनी पड़ती है। स्टेज पर गाते समय री-टेक नहीं होता, 'जो एक बार गाया, वही फाइनल होता है' लेकिन फिल्म या टी०वी० सीरियल में ऐसा नहीं है। यदि डायरेक्टर को कोई सीन उसके मुताबिक नहीं जंच रहा है, तो वह चाहे जितनी बार भी री-टेक करा सकता है। पार्श्वगायन में भी यही बात है।

माया: और कितने सीरियलों में काम कर रहे हैं?

अनूप: बस, फिलहाल तो यही 'अदालत' है। आफर आते हैं, लेकिन समय न होने के कारण मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं।

माया: इस समय कितनी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं और गा रहे हैं?

अनूप: 'सूरदास चिंतामणि', 'आ जा मेरे लाल', 'तोहफा मोहब्बत का' में अभिनय भी किया और गाया भी है। कुछ में संगीत भी दे रहा हूं। ये फिल्में शीघ्र ही रिलीज होने वाली हैं। इनके अलावा 'बुनियाद', 'काला जल' और 'कहां गये वो लोग' टी०वी० सीरियलों में 'टाइटिल सांग' गाये हैं।

प्रस्तुति: महादेव शर्मा

एन०टी०आर० की नकल

छाया : रंजन बसु

मुलायम सिंह का 'क्रांति-रथ'

रथों की राजनीति में एक और रथ

आंध्र प्रदेश में एन०टी० रामाराव के 'चैतन्य रथ' और हरियाणा में देवीलाल के 'विजय रथ'की दिग्विजय से प्रेरित होकर लोकदल के नेता मुलायम सिंह यादव भी 'क्रांतिरथ' बनवाकर 'क्रांति' करने के लिए उत्तर प्रदेश के भीतरी इलाकों की यात्रा पर निकल रहे हैं। कैसा है, उनका क्रांति रथ ? क्या रामाराव व देवीलाल की तरह रथ-यात्राओं की राजनीति में जुड़ा एक और रथ मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में 'क्रांति का मसीहा' बना पायेगा ? :

दूर से देखने में पूरा दृश्य किसी भी मोटर बाडी बिल्डर्स के बड़े गैराज जैसा ही था, जहां तमाम बसों व ट्रकों का ढांचा तैयार किया जाता है। लेकिन, राजधानी के एक कोने में 'एसोसियेटेड आटो बिल्डर्स' की वर्कशाप में खड़ी नयी 'टाटा मर्सिडीस' पर खड़ा किया जा रहा ढांचा किसी आम मिनी बस का नहीं है। शायद यही कारण है कि इसके निर्माण में दिन रात जुटे कारीगरों का अन्दाज, तेवर और उत्साह भी अलग है। ठेकेदार त्रिलोक चन्द्र गर्वीले स्वर में 'माया' से कहते हैं, "साहब, यह हिंदुस्तान में अपने तरह की पहली गाड़ी होगी।"

लेकिन, पिछले एक महीने से दिन-रात मेहनत कर रहे मिस्त्रियों-मैकेनिकों में अधिकांश को यह नहीं पता है कि वह जिस 'गाड़ी' को तैयार कर रहे हैं, उसका क्या होगा ? उन्हें सिर्फ यह पता है कि वह कुछ 'अलग चीज' बना रहे हैं। एक ऐसी गाड़ी जो उन्होंने अब तक न देखी है और न बनायी है। हथौड़ा बजाते हुए चन्द्रजीत का कहना था, "यह नेताजी की गाड़ी बन रही है।" लेकिन नेताजी का नाम क्या है, किस पार्टी के हैं और इस गाड़ी का क्या करेंगे ? यह वह नहीं जानता और न ही यह जानने की उसे विशेष उत्सुकता है। वह इससे बेहद उत्साहित है कि इस गाड़ी में ऐसा 'सिस्टम' होगा कि बटन दबाते ही गाड़ी की छत में छेद हो जायेगा और अन्दर खड़ा आदमी खटाक से अपने-आप छत पर पहुंच जायेगा।

चन्द्रजीत की तरह दिन-रात उत्साह के साथ इस गाड़ी को बना रहे अन्य मजदूरों को भी शायद यह पता नहीं है कि उनके द्वारा निर्मित यह गाड़ी, अपने किस्म की सिर्फ एक दिलचस्प वाहन ही नहीं होगी, जिसमें तमाम तकनीकी प्रयोग किये गये

हैं, बल्कि गंगा-यमुना की घाटी में किये जा रहे, एक नये राजनीतिक प्रयोग की वाहक भी होगी। आंध्र प्रदेश के नेता-अभिनेता नम्बूदरि तारक रामाराव के चैतन्य रथ की सफलता तथा हरियाणा चुनाव में देवीलाल द्वारा चलाये गये 'विजय रथों' के बाद अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महाभारत में जूझते मुलायम सिंह यादव अपने लिए 'क्रांति रथ' का निर्माण करवा रहे हैं।

रथों की परिकल्पना और प्रयोग-परम्परा भले ही कितनी पुरातन हो, किंतु आधुनिक भारतीय राजनीति में रथों की पुनर्स्थापना पिछले कुछ ही वर्षों में शुरू हुई राजनीति की नयी शैली का प्रतिफल हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी तथा उसके नेता एन०टी० रामाराव के चमत्कारी राजनीतिक अभ्युदय के साथ ही रामाराव का ''चैतन्य रथ' न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश में चर्चित हो गया था। वरन रामाराव की रथ-राजनीति की इस शैली को काफी समय तक उत्तर भारत में किसी नेता ने नहीं दोहराया। बहुत बाद में हरियाणा संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन के अंतिम चरण में ठीक चुनाव से पहले पहली बार चौधरी देवीलाल को यह सूझा कि रामाराव के तरीके से उन्हें भी रथ पर चलना चाहिए। हरियाणा चुनाव में चल रही कांग्रेस-विरोधी आंधी के बीच उतरे देवीलाल के रथों ने उन्हें चुनाव जितवाने में कितनी मदद की, यह कहना तो कठिन है किंतु आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की भारी शिकस्त के बाद यह रथ जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं के मन में एक शुभ चिन्ह बन गया, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में संकट की पूर्वसूचना देने-वाला अशुभ प्रतीक। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने के लिए एन०टी० रामाराव भी अपने चैतन्य रथ के साथ आये थे।

कीमती रथ : उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए मुलायम सिंह द्वारा बनवाया जा रहा यह रथ जहां एक तरफ अब तक चर्चित रथों में सबसे नया रथ होगा, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी रूप से सर्वाधिक विशिष्ट तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इस रथ में ऐसी कई तकनीकी विशिष्टताओं को जोड़ा गया है जो अब तक के बने किसी भी रथ में मौजूद नहीं। यही कारण है कि यह अब तक बने सभी रथों से ज्यादा कीमती भी है। किंतु, इस सबसे ज्यादा जो बात इस रथ को विशिष्ट बनाती है, वह इसका तकनीकी पक्ष न होकर राजनीतिक पक्ष है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय राजनीति के हृदयस्थल उत्तर प्रदेश में घूमने वाला यह रथ जहां एक तरफ उत्तर भारत की राजनीति में अपने किस्म का पहला प्रयोग होगा, वहीं बहुत हद तक भारतीय राजनीति की भावी धारा को प्रभावित करने वाला भी।

टाटा मर्सिडीस मिनी बस पर लगभग ८ लाख रुपए की लागत से तैयार किये जा रहे, इस रथ का निर्माण करीब दो महीने के कठिन परिश्रम के बाद पूरा हो पाया है। इस रथ की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें लगाया गया हाइड्रोलिक लिफ्ट मंच, जिसके द्वारा इस रथ में यह व्यवस्था है कि जब गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अंदर ही बने एक छोटे से प्लेटफार्म पर खड़ा होकर रिमोट-कंट्रोल से बटन दबायेगा, तो वह प्लेटफार्म अपने आप उस आदमी को उठाकर ऊपर छत तक ले जायेगा। यानी इस रथ में बैठे नेता को और ऊंचे मंच तक पहुंचने के लिए न एक कदम चलना होगा और न ही एक क्षण नष्ट करना होगा। इस प्रक्रिया में गाड़ी के अंदर प्लेटफार्म के ऊपर का छत का हिस्सा और ऊपर उठकर एक छत्र का रूप ले लेगा। गाड़ी की ही छत पर उस प्लेटफार्म की सतह पर एक बड़ा मंच भी बनाया जा रहा है ताकि यदि एक से अधिक व्यक्तियों को किसी सभा में भाषण देना हो, तो उस लिफ्ट प्लेटफार्म से एक-एक करके रथ के अंदर बैठे नेता छत पर बने मंच तक पहुंच सकें। रथ के ऊपर उठे हुए प्लेटफार्म के मंच को भाषण देने के बाद नेता अपने हाथ में मौजूद छोटे से रिमोट-कंट्रोल का बटन दबाते ही नीचे ला सकता है। इसी के साथ प्लेटफार्म मंच के ऊपर बना हुआ छत्र गाड़ी की छत के एक सामान्य हिस्से के रूप में जुड़कर छत को बंद कर देता है तथा एक क्षण पूर्व मंच पर भाषण दे रहा हुआ नेता गाड़ी के अंदर बने अपने वातानुकूलित कमरे में पहुंच जाता है।

> रथों की परिकल्पना और प्रयोग-परंपरा भले ही कितनी पुरातन हो, किंतु आधुनिक भारतीय राजनीति में रथों की पुनर्स्थापना पिछले कुछ ही वर्षों में शुरू हुई राजनीति की नयी शैली का प्रतिफल हैं।

रथ का निर्माण कर रहे एसोसिएटेड आटो बिल्डर्स के मालिक शमशेर सिंह तथा राजेन्द्र सिंह अरोड़ा का 'माया' से कहना था कि हिंदुस्तान में किसी भी मिनी बस में इस तरह का हाइड्रोलिक लिफ्ट मंच कभी नहीं लगाया गया है। यह हम लोगों द्वारा किया गया पहला प्रयोग है। रथ के लिए इंडियन हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज से विशेष तौर पर आर्डर देकर यह लिफ्ट मंच तैयार करवाया गया है, जिसे गाड़ी के गेयर बाक्स के ऊपर लगाया गया है। इस मंच का विचार देनेवाले नवल सिंह का 'माया' से कहना था कि जब हमने इस विचार के साथ ऐसी लिफ्ट लगी गाड़ी तैयार करने के लिए राजधानी के तमाम आटो बिल्डर्स से कहा, तो सभी ने इस विचार को अव्यावहारिक मानते हुए ऐसा रथ बना पाने से इंकार कर दिया। किंतु धुन के पक्के नवल सिंह एसोसिएट आटो बिल्डर्स के इंजीनियरों को यह समझाने में सफल हो गये कि इस तकनीकी तिकड़म के द्वारा गाड़ी में ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सकती है।

भीतरी कक्ष : इसके अतिरिक्त इस रथ में एक ओर आगे नेता के बैठने के लिए एक वातानुकूलित कक्ष होगा तथा दूसरी ओर रिवाल्विंग (घूमने वाला) दूरदर्शन व वीडियो सेट। इसके द्वारा सभाओं में जहां एक तरफ दूरदर्शन के स्क्रीन को बाहर की तरफ घुमाकर जनता को वीडियो प्रचार फिल्में दिखायी जा सकती हैं, वहीं यात्रा के समय उसे गाड़ी के अंदर घुमा करके उसके द्वारा नेता अपनी पूर्व सभा में दिये गये भाषण व जनता की प्रतिक्रियाओं के टेप देख सकता है। ऐसी तमाम आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त इस रथ में कुल ११ व्यक्तियों के बैठने या उससे कुछ कम व्यक्तियों के सोने की व्यवस्था है। मुलायम सिंह यादव के इस रथ में एक सीट उनके अंगरक्षक के बैठने के लिए अलग से बनायी गयी है। पहले इसमें एक छोटा-सा स्नानागार व शौचालय भी बनाये जाने की योजना थी, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव द्वारा पसंद न किये जाने के कारण उसे हटाकर केवल एक वासबेसिन और प्रसाधन शीशा लगा दिया गया है। गाड़ी में ही लाउडस्पीकर तथा तेज सर्चलाइटों की भी व्यवस्था की गयी है, ताकि ऐसे दूरदराज क्षेत्रों में जहां प्रायः विद्युत आपूर्ति नहीं रहती, वहां भी देर रात की सभायें संबोधित की जा सकें।

क्रांति-यात्रा : अपने किस्म के इस अजूबे रथ पर आरूढ़ मुलायम सिंह यादव १४ सितंबर को कानपुर से अपनी क्रांति-यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वह २८ दिन के अंदर राज्य के लगभग ४० जिलों की यात्रा करेंगे। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित क्रांतिकारी मोर्चे द्वारा संचालित क्रांति-यात्रा के अंतिम चरण में १५ अक्तूबर को यह क्रांति रथ लखनऊ पहुंचेगा किंतु क्या यह दक्षिण के 'चैतन्य रथ' की तरह उत्तर भारत की राजनीति में किसी नयी राजनीतिक धारा का भी वाहक बन पायेगा ? शायद इसका उत्तर अभी दे पाना कठिन होगा। फिलहाल तकनीकी रूप से विशिष्ट यह 'क्रांति-रथ' अपनी राजनीतिक विशिष्टता तभी प्राप्त कर पायेगा, जब यह उत्तर भारत के ग्रामीणों के लिए मात्र एक कौतुक व आकर्षण का केंद्र मात्र न रहकर एक राजनीतिक आंदोलन का अग्रवाहक बन जाये जो रथ की जगह इस पर निर्भर करेगा कि उस पर बैठे महारथी और सारथी को कितनी राजनीतिक महारत हासिल है।

—पुनीत टण्डन

उत्तर प्रदेश के मनमोहक पर्वतांचल में आइये

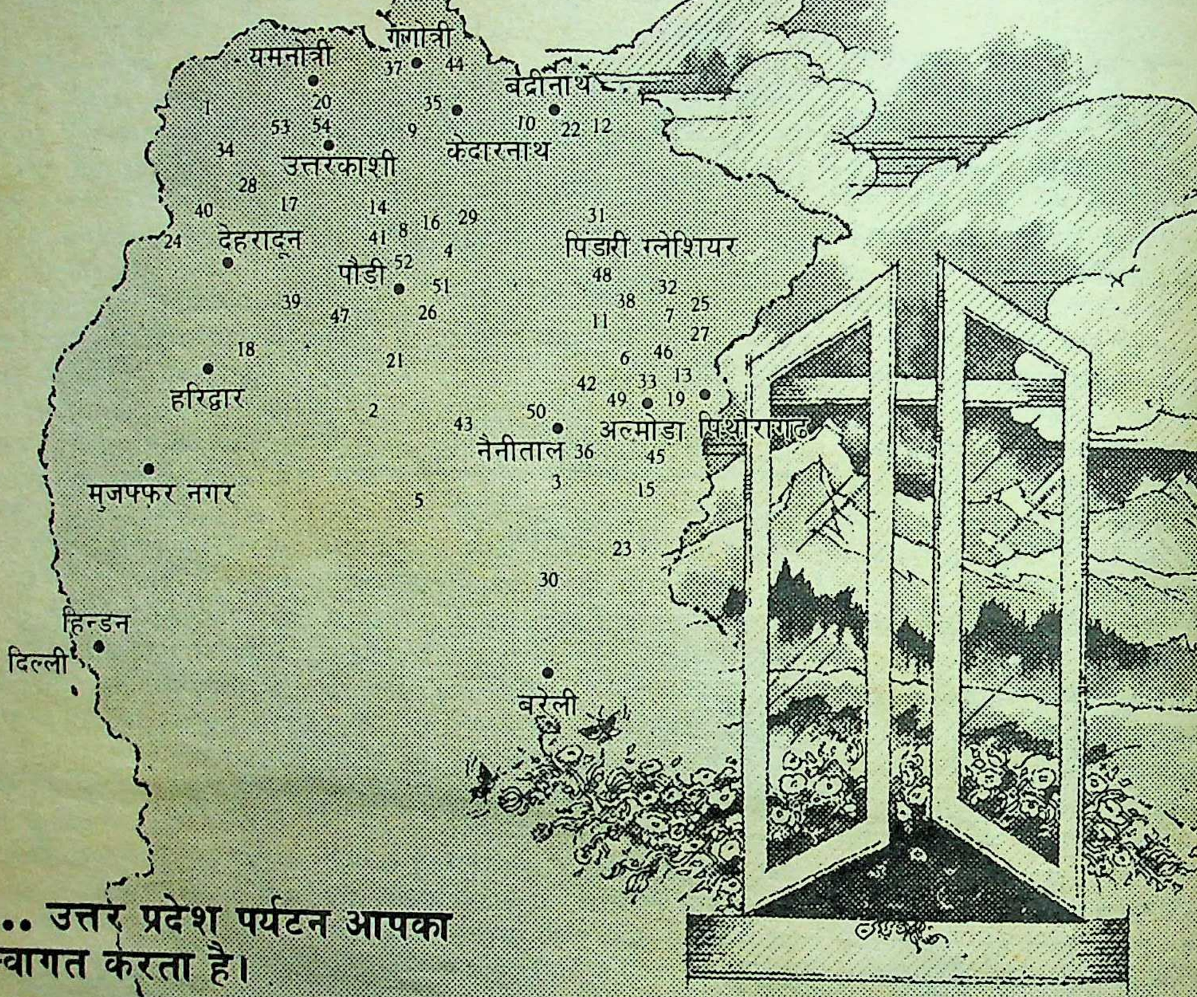
गंगोत्री
यमनोत्री
बद्रीनाथ
उत्तरकाशी
केदारनाथ
देहरादून
पौड़ी
पिंडारी ग्लेशियर
हरिद्वार
अल्मोड़ा
पिथौरागढ़
नैनीताल
मुजफ्फर नगर
हिन्डन
दिल्ली
बरेली
37 44 1 20 35 53 54 9 10 22 12 34 28 17 14 16 29 40 41 8 31 24 4 52 48 51 38 32 25 39 47 26 11 7 27 18 6 46 21 42 33 13 49 19 2 50 43 36 45 3 15 5 23 30

... उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है।

यदि आप बहुविध आकर्षणों वाले उत्तर प्रदेश के पर्वतांचल की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हों तो विलम्ब मत कीजिये। विस्तृत भू-भाग में फैले इस क्षेत्र में प्राकृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक आकर्षणों का अद्भुत संगम है। क्या नहीं है यहाँ देखने व घूमने के लिये?

यहां के पर्यटन स्थलों पर आकर आपको सन्तोष और आनन्द की जो अनुभूति होगी, उसको द्विगुणित करेगी उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 63 स्थानों पर स्थापित विश्राम गृहों की उत्तम व आरामदायक व्यवस्था।

1) आराकोट 2) कोटद्वार 3) काठगोदाम 4) कर्ण प्रयाग 5) काशीपुर 6) कौसानी 7) खाटी 8) गौचर 9) गुप्त काशी 10) गौरीकुंड 11) ग्वालदम 12) घंघरिया 13) चौकोरी 14) चन्द्रपुरी 15) चम्पावत 16) चोप्ता 17) चम्बा 18) चीला 19) जागेश्वर 20) जानकी चट्टी 21) ज्वाल्पाधाम 22) जोशीमठ 23) टनकपुर 24) डाक पत्थर 25) द्वाली 26) देव प्रयाग 27) धाकुरी 28) धनोल्टी 29) नन्द प्रयाग 30) नानकमत्ता 31) पीपल कोटी 32) फरकिया 33) बागेश्वर 34) बड़कोट 35) भोजवासा 36) भीमताल 37) भैरोघाटी 38) मुंडोली 39) मुनीकीरेती 40) मसूरी 41) रुद्रप्रयाग 42) रानीखेत 43) रामनगर 44) लंका 45) लोहाघाट 46) लोहार खेत 47) लेंसडाउन 48) वाण 49) शीतला खेत 50) सातताल 51) सोन प्रयाग 52) श्रीनगर 53) समानाचट्टी 54) हनुमान चट्टी

उत्तर प्रदेश में हर जगह जहाँ आप ठहरना चाहें।

इस कूपन को काटकर हमें भेज दें।

कृपया अपने आवास गृहों से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी दें।
नाम ....
पता: ....
इच्छित भाषा: अंग्रेजी/हिन्दी

अधिक जानकारी के लिये लिखें

उत्तर प्रदेश पर्यटन,
चित्रहार भवन 3-नवल किशोर मार्ग,
लखनऊ-226001 फोन: 48349, 45252, 47749

- तत्कालिक आरक्षण केन्द्र चन्द्रलोक भवन,
  36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 फोन: 322251.
- गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड
  74/1 राजपुर मार्ग, देहरादून, उ.प्र. फोन: 26817
- कुमांऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड
  सकेट्रियेट बिल्डिंग, नैनीताल, उ.प्र. फोन: 2509

F.N.XIII/-1262

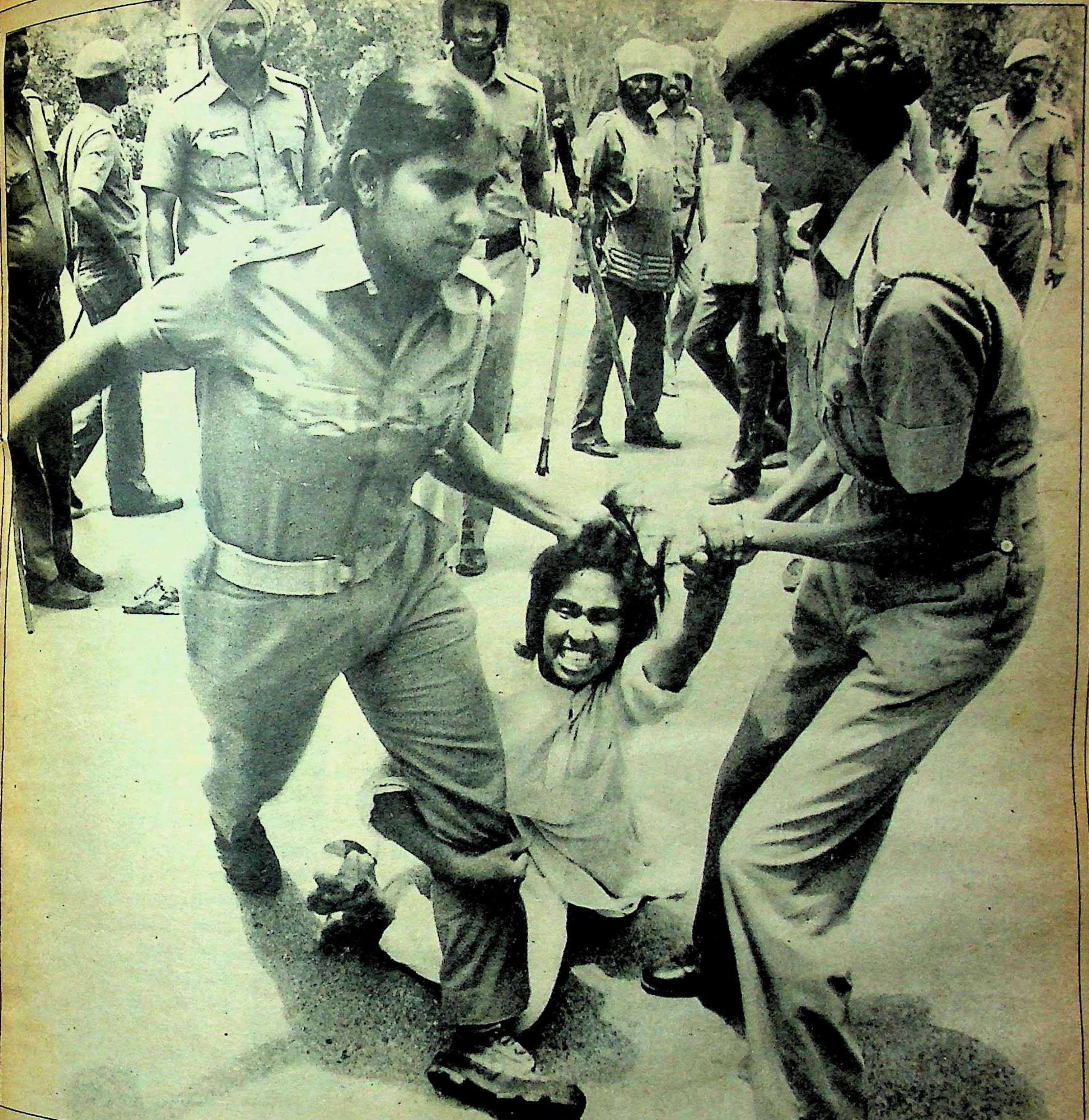

छाया : रंजनबसु

सरकार को महिलाओं की इज्जत का खास खयाल है। इसलिए उसने हाल में महिला केंद्रीय सुरक्षित पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) का गठन किया है, जिससे महिलाएं, पुरुष पुलिस बल की बदसलूकी और निर्ममता की शिकार न हों। लेकिन लगता है पुलिस की वरदी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि चाहे इसे पुरुष पहने या महिला—पुलिस, पुलिस ही रहेगी। नजारा आपके सामने है। ये दो वीरांगनाएं जो एक महिला पर अपना जौहर दिखा रही हैं, नवगठित महिला सी०आर०पी०एफ० की ही हैं। यह महिला न आतंकवादी है और न खूंख्वार अपराधी—इसका कसूर यह है कि यह आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली में आयोजित जुलूस में शामिल थी। दु:शासन को बड़ी शर्म आ रही होगी जो 'पराक्रम' उसने अपने दरबार में दिखाया था, वह अब सरेआम दिखाया जा रहा है और वह भी महिलाओं द्वारा!

डा० सच्चिदानंद राउतराय

अगस्त माह का अंतिम सप्ताह यदि पुरस्कारों का सप्ताह कहा जाये, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। २६ अगस्त को उड़िया कवि डा० सच्चिदानंद राउतराय को डेढ़ लाख की राशि वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गयी, तो २७ अगस्त को नागालैंड के नटवर ठक्कर को रचनात्मक कार्यों के लिए, महाराष्ट्र के सुनीत बोंडे को ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए और मद्रास की श्रीमती अन्नाप्रगदा कृष्णराव को महिला व बाल-कल्याण के क्षेत्र में योगदान देने पर एक लाख रुपए, एक पदक और एक प्रशस्ति-पत्र वाला वर्ष १९८७ का जमना लाल बजाज पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गयी। २९ अगस्त को एक लाख रुपए, स्वर्ण कमल और एक प्रशस्ति पत्र वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार बी० नागी रेड्डी को दिये जाने की घोषणा हुई।

भारतीय साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार (१९८६) पानेवाले उड़िया के शीर्षस्थ साहित्यकार डा० सच्चिदानंद राउतराय उड़िया साहित्य में काव्य-मुक्ति के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने कविता को छंद, तुक व अलंकरण से मुक्ति दिलायी।

सची राउतराय के नाम से लोकप्रिय डा० सच्चिदानंद राउतराय का कविता के प्रति रुझान बचपन से ही था। जब वह १२ वर्ष के थे, तभी उनकी पहली कविता १९२८ में एक उड़िया पत्रिका में प्रकाशित हुई। १९३२ में उनका पहला कविता संग्रह 'पाथेय' तब प्रकाशित हुआ जब वह माध्यमिक स्कूल के छात्र थे। १९२८ से कविता की दुनिया में आनेवाले राउतराय के अब तक १६ उल्लेखनीय काव्य-संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा उनकी कथा-साहित्य, काव्य-नाटक, आलोचना और शोध की अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

कविता संग्रह 'पाथेय' और 'पाण्डुलिपि' द्वारा उड़िया साहित्य में नवयुग और नयी कविता का द्वार खोलकर राउतराय ने इस नयी प्रवृत्ति को और भी स्पष्ट और मूर्त रूप दिया, अपने कविता संग्रह 'कविता १९६२' के जरिये।

आधुनिक उड़िया कविता के भगीरथ कहे जाने वाले राउतराय परंपरावादी काव्य और नवोत्थानवादी धारा से विलग होकर नयी-नयी शैलियों का प्रयोग करते रहे हैं, जिससे उनकी कविता अभिधा से उत्तरोतर वस्तुपरक अभिव्यंजनाओं की ओर उन्मुख होती गयी। बिम्ब योजना में पारंगत राउतराय ने वर्ण, ध्वनि तथा आकृतियों पर आधारित भांति-भांति के बिम्बों का प्रयोग किया और प्रारंभ से ही मुक्तछंद का विकास किया।

राउतराय का जितना योगदान उड़िया कविता के प्रति है, उतना ही आधुनिक उड़िया गद्य के प्रति भी। उनके ग्रंथ 'साहित्य विचार', 'साहित्यरमूल्य बोध' और 'आधुनिक साहित्यरकेतर दिग' साहित्य के अनुशीलन-अध्ययन के क्षेत्र में अमूल्य माने जाते हैं।

१९८६ के लिए राउतराय को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार २२ वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार हिंदी और कन्नड़ के बाद बंगला और मलयालम को तीन-तीन बार, गुजराती को दो बार और असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी व उर्दू भाषा के साहित्यकारों को एक-एक बार मिल चुका है। राउतराय उड़िया के दूसरे साहित्यकार हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान मिला है। इसके पूर्व नौवां ज्ञानपीठ पुरस्कार १९७३ में गोपीनाथ महंती को मिला था।

पांच दशक से भी अधिक समय से उड़िया कविता से जुड़े राउतराय का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान सिर्फ उनका ही सम्मान नहीं है, बल्कि उनके साथ ही उड़िया कविता के नये युग और नयी संवेदना का भी सम्मान है, क्योंकि संभवत: राउतराय के बगैर आधुनिक उड़िया कविता सभव नहीं थी।

बी० नागी रेड्डी

फिल्म-विधा से जुड़े किसी भी व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने का मतलब है कि उस व्यक्ति की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन हुआ है। हिंदी फिल्मों के युग प्रवर्तक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के सम्मान में जब १९७० में भारतीय सिने कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फिल्मकारों के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ, तो पहला पुरस्कार मिला देविका रानी को। और अब, इस सम्मान के हकदार हुए ७५ वर्षीय बी० नागी रेड्डी।

तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में लगभग ४० फिल्मों के निर्माता बी० नागी रेड्डी ऐसे परिवार से हैं, जहां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले वह अकेले सदस्य नहीं हैं। १९७५ में बी० नागी रेड्डी के बड़े भाई बी०एन० रेड्डी को तेलुगु सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है।

बी० नागी रेड्डी का वाहुनि स्टूडियो एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्टूडियो माना जाता है। १९४५ में बी० नागी रेड्डी ने पहली तेलुगु फिल्म 'साहूकार' का निर्माण किया। रेड्डी १९६४ में हिंदी सिनेमा से जुड़े और उन्होंने 'घर-घर की कहानी', 'राम और श्याम', 'नन्हा फरिश्ता', 'जूली' और 'श्रीमान-श्रीमती' जैसी सफल फिल्में बनायीं।

बी० नागी रेड्डी के पूर्व देविका रानी (अभिनेत्री), पृथ्वीराज कपूर (अभिनेता), बी०एन० सरकार (निर्माता), कानन देवी (अभिनेत्री), नितिन बोस (निर्देशक), नौशाद (संगीतकार), एल०वी० प्रसाद (निर्माता) सत्यजीत राय (निर्देशक), बी० एन० रेड्डी (निर्माता) और वी० शांताराम (अभिनेता, निर्देशक, निर्माता) जैसी फिल्मी हस्तियां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं।

—दिनेश दीनू

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

ज770/15

3,00,00,000 तीन करोड़ से अधिक पाठकों की पसंद

प्रिय अभिभावक,
आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है,
अंग्रेजी अच्छी तरह लिख-पढ़ लेता है;
उसकी एकमात्र समस्या.......
वह इसे बोलने में हिचकता या अटकता है!

इसका समाधान बता रहे हैं
उसके प्रिय खिलाड़ी **कपिल देव**–

"अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एकमात्र सोर्स
रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स "

New
Addition
LETTER
WRITING

बड़े साइजं के
400 से अधिक पृष्ठ
मूल्य: 28/- प्रत्येक
डाकखर्च: 5/- प्रत्येक
12 भारतीय
भाषाओं में प्रकाशित

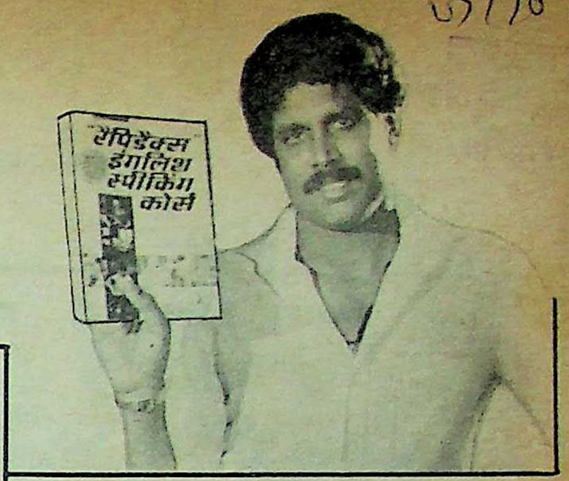
रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स

It's really a good book to learn
spoken English —**Kapil Dev**

होम डेकोरेशन गाइड

होम डेकोरेशन गाइड

इस पुस्तक में गृह-सज्जा संबंधी प्राय: सभी विषयों को विस्तारपूर्वक और चित्रों सहित भली-भांति समझाया गया है।

मूल्य: 20/- डाकखर्च: 4/-

101 SCIENCE GAMES
101 साइंस गेम्स

101 साइंस गेम्स

खेल-खेल में वैज्ञानिक उपकरण बनाना सिखाने वाली एक ऐसी पुस्तक, जो बच्चों की रुचि विज्ञान में जगाएगी।

मूल्य: 15/- डाकखर्च: 4/-

विश्व-प्रसिद्ध युद्ध

विश्व-प्रसिद्ध युद्ध

अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर हुए युद्धों का सचित्र प्रामाणिक संकलन (नक्शों सहित)

मूल्य: 12/- डाकखर्च: 3/-

SELF
LETTER
DRAFTING
COURSE

**सेल्फ
लैटर ड्राफ्टिंग कोर्स**

अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी में 'लैटर्स' को 'ड्राफ्ट' करने के लिए 'रेडीमेड' वाक्य दिये गये हैं।

मूल्य: 28/- डाकखर्च: 5/-

संसार के 1500 अद्भुत आश्चर्य

**संसार के
1500 अद्भुत आश्चर्य**

प्रकृति के आश्चर्यजनक चमत्कारों का पिटारा– जीव जंतुओं, वनस्पतियों, मनुष्यों की ढेरों विचित्रताएं

मूल्य: 25/- डाकखर्च: 4/-

अपना कद बढ़ाइये

इस कोर्स की मदद से कुछ ही हफ्तों में आपकी लंबाई निश्चित रूप से 10 सेमी तो बढ़ ही जायेगी।

मूल्य: 15/- डाकखर्च: 4/-

विश्व के विचित्र जीव-जंतु

**विश्व के
विचित्र जीव-जन्तु**

75 से भी अधिक विचित्र जीव-जंतुओं के बारे में ऐसी सचित्र जानकारी, जिसे पढ़कर आप हैरत में पड़ जाएंगे।

मूल्य: 15/- डाकखर्च: 4/-

जूडो-कराटे

आत्मरक्षा के गुर सिखा कर, बिना हथियार गुण्डों से अपना बचाव करने की जापानी कलाएं सिखाने वाली एक अनूठी पुस्तक।

मूल्य: 15/- डाकखर्च: 4/-

51 महान आविष्कार

51 महान् आविष्कार

हजारों साल पुराने पहिये से लेकर कम्प्यूटर, रॉकेट तक के आधुनिकतम आविष्कारों का सचित्र लेखा-जोखा।

मूल्य: 20/- डाकखर्च: 4/-

ट्रिक फोटोग्राफी एण्ड कलर प्रोसेसिंग

**ट्रिक फोटोग्राफी
एण्ड कलर प्रोसेसिंग**

ट्रिक फोटोग्राफी पर हिन्दी में प्रथम पुस्तक, जिसमें ट्रिक और इफेक्ट (Effect) की पूर्ण जानकारी दी गई है।

मूल्य: 21/- डाकखर्च: 4/-

**डा० श्रीमाली की दो
प्रामाणिक पुस्तकें**

वृहद् हस्तरेखा शास्त्र

पुस्तक की सहायता से आप भाग्य की रेखाएं एक पुस्तक की तरह पढ़ कर भूत व भविष्य जान सकते हैं।

मूल्य: 24/- डाकखर्च: 4/-

PRACTICAL PALMISTRY
वृहद हस्तरेखा शास्त्र

PRAC HYPN
प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म

प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म

सम्मोहन विद्या पर प्रामाणिक ग्रंथ, जो साधारण पाठक को भी इस गुप्त विद्या का विशेषज्ञ बना सकता है।

English Edition Price: Rs. 30/-

मूल्य: 24/- डाकखर्च: 4/-

इन्कमटैक्स बचाने के 101 तरीके

**टैक्स प्लानिंग द्वारा
इन्कम-टैक्स बचाने
के 101 तरीके**

ऐसी जानकारियां, जिनसे दो लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कानूनी ढंग से टैक्स से बचा सकते हैं।

मूल्य: 20/- डाकखर्च: 4/-

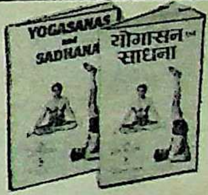
YOGASANAS and SADHANA
योगासन एवं साधना

योगासन एवं साधना

'भारतीय योग संस्थान' के योगाचार्यों द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवों के आधार पर लिखित अनूठी पुस्तक।

मूल्य: 10/- डाकखर्च: 3/-

**विश्व-प्रसिद्ध
रोमांचक कारनामे**

कुछ कर गुजरने के लिए उकसाने वाले रोमांचक कारनामे (Adventures)

मूल्य: 12/- डाकखर्च: 3/-

रैपिडैक्स होम टेलरिंग कोर्स

**रैपिडैक्स
होम टेलरिंग कोर्स**

दर्जियों जैसी टेलरिंग सिखाने वाला एक ऐसा प्रभावी कोर्स, जिसमें 175 से भी अधिक पोशाकों के नवीनतम नमूने हैं।

मूल्य: 32/- डाकखर्च: 5/-

**चिल्ड्रन्स
ट्रिक्स एण्ड स्टंट्स**

करने में आसान ऐसी 70 रहस्यमय ट्रिक्स, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सभी का भरपूर मनोरंजन करेंगी।

मूल्य: 12/- डाकखर्च: 3/-

मॉडर्न कुकरी बुक

पाक-कला विशेषज्ञा श्रीमती आशारानी व्होरा द्वारा लिखित 100 से भी अधिक लोकप्रिय व्यंजन-विधियां।

मूल्य: 15/- डाकखर्च: 4/-

अपने निकट के बुकस्टाल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुकस्टालों पर मांग करें या वी.पी.पी. द्वारा मंगाने के लिए लिखें:

पुस्तक महल

10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002
खारी बावली, दिल्ली–110006

रॉयल गव्हर्नमेंट ऑफ भुटान का सचमुच राजेशाही

दिवाली बंपर

जितिए!

प्रथम पुरस्कार रु.

१ करोड़

द्वितीय पुरस्कार: (१) रु. २५ लाख

तृतीय पुरस्कार: (१०) रु. ५ लाख

चतुर्थ पुरस्कार: १ लाख के १०० पुरस्कार

टिकट: रु. १००/– ड्रॉ: २७-१०-८७

स्त्रोत पर आयकर की कटौती नही

कुल पुरस्कार:

रु: ५ करोड

ऑर्गनायझर:
पायोनियर लॉटरीज्
दिल्ली, मद्रास, बँगलोर

सोल स्टॉकीस्ट:
संजय एजन्सी
एफं/७९, भगतसिंग मार्केट,
नई दिल्ली–११० ००१.

पी. एचू. जैन
मॅजेस्टीक लॉटरी स्टोअर्स
चंद्रमहल, २४१, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
बम्बई-४०० ००२. फोन: २९०६१३

प्रस्तूतकर्ता: असि. सेक्रेटरी, रॉयल गव्हर्नमेंट ऑफ़ भुटान लॉटरीज़, फुन्टशोलींग, भुटान.

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक १९

अक्तूबर प्रथम पक्ष १९८७

माया

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१,
५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय
३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन:
३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-
१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-
२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-
रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा
सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी
सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया
कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-
ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

यह अंक

राजीव बनाम गोयनका
क्या भारत यह कप जीत पायेगा?

२६

आवरण कथा

१९८३ में प्रुडेंशियल कप जीतनेवाली भारतीय टीम के सामने रिलायंस कप इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। क्या भारत उन स्वर्णिम क्षणों को अपनी जमीन पर भी दोहरा पायेगा? भाग लेने वाली अन्य टीमों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय टीम की तैयारियों और संभावनाओं का विश्लेषण प्रसिद्ध खेल विशेषज्ञ डा० नरोत्तम पुरी द्वारा:

राजीव बनाम गोयनका
इंडियन एक्सप्रेस, पर छापों के बाद शुरू हुए गोयनका-राजीव के युद्ध का जायजा: ४२

आदिवासी महिलाओं का शोषण
ठेकेदारों द्वारा यौन शोषण की शिकार आदिवासी महिलाओं की व्यथा
कथा: ६५

सती प्रकरण
रूपकंवर को अपने मृत पति के साथ आत्मदाह करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? सती-विवाद की भीतरी पड़ताल: ८२

दिल्ली
'न्याय यात्रा' और 'न्याय युद्ध' के जरिये भाजपा ने दिल्ली में इंका के खिलाफ क्या माहौल बनाया है? ६६

मध्य प्रदेश
सरकार की आमदनी का प्रमुख स्रोत आबकारी विभाग चालू सत्र में पौने दो करोड़ रुपए के घाटे में क्यों है? ५९

बोफोर्स
बोफोर्स के मोरबर्ग की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या राजीव गांधी को 'क्लीन चिट' दिलवाना मात्र था? ७३

दिल्ली दरबार: राम खिलावन बनारसी पानवाला भी ले आया बोफोर्स से चिट्ठी ६
फोटोफीचर ९
रिलायंस कप: सबसे महंगी क्रिकेट प्रतियोगिता १३
एन०के०पी० साल्वे से साक्षात्कार १४
अनिल अंबानी और बापू नाडकर्णी से साक्षात्कार १५
रिलायंस कप: खेल की शर्तें १६
फर्क पांच दिवसीय और एक दिवसीय क्रिकेट का १९
सबसे मजबूत दावा पाकिस्तान का है २०
सेमीफाइनल तक आस्ट्रेलिया पहुंचेगा! २१
इंग्लैण्ड का पलड़ा भी भारी है २२
क्या वेस्टइंडीज तीसरी बार विश्वकप जीतेगा? २३
मीडिया: जिम्मेदारी और चुनौतियां २९
संभावनाएं नौसिखिया टीमों की ३०
टीम का चयन कैसे होता है? ३१
विकेट कीपर की भूमिका निर्णायक होती है ३२
फिर याद आयेगी कपिल की मैराथन पारी ३४
दर्शकों का व्यवहार खेल को खेल बना सकता है ४०
उत्तर प्रदेश: दिल्ली दरबार जब अमेठी पहुंचा! ६१
विशेष रिपोर्ट: धर्म के नाम पर स्त्री वहन ८२
परदे के पीछे ९४
दूरदर्शन: छोटे परदे पर खूनी क्रिकेट ९७

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

माया
ठाकुर बनाम ब्राह्मण: शामत राजाओं की या राजीव की ?
विकल्प की तलाश में विपक्ष

ठाकुर बनाम ब्राह्मण : शामत राजाओं की या राज़ीव की ?

३० सितंबर, की आवरण कथा 'ठाकुर बनाम ब्राह्मण : शामत राजाओं की या राजीव की ?' पढ़ी। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामत न राजाओं की आयेगी न राजीव की, वरन अप्रत्यक्ष रूप से शामत देश की गरीब जनता की ही आयेगी। आज राज्यों और केंद्र सरकार में बैठे नेता इन सबसे आंखें मूंदे राजनीतिक जोड़-तोड़ में लगे हैं। देश को स्वर्ग बनाने का सपना दिखाने वाला राजनेता आज जातिवाद एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं कुर्सी से चिपके रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, इससे चाहे राष्ट्र का हित हो या अहित ! जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अपनी सारी शक्ति एवं सूझ-बूझ एक प्रतिभाशाली एवं विकास शील राष्ट्र के निर्माण में लगायें जिससे न कोई गरीब रहे और न कोई बेरोजगार एवं राष्ट्र सुख-समृद्धि को प्राप्त हो।

उक्त आवरण कथा में राजाओं और राजीव की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की दौड़ का जो चित्रण किया गया है, पढ़कर लगा हमारे राजनेता, जिन्हें हम चुनकर इस आशा से भेजते हैं कि वे राष्ट्र हित में अपना योगदान देंगे परंतु ऐसा नहीं होता। ये राजनेता चाहे वे राजा हों या स्वयं राजीव राष्ट्र-हित की उपेक्षा कर अपने एवं परिवार के हितों का ज्यादा ध्यान देते हैं। —इसरार खां, ई-३/६४८, सेक्टर (आई०), अलीगंज, लखनऊ।

३० सितंबर की 'माया' में प्रकाशित सामग्री, आवरण कथा ठाकुर बनाम ब्राह्मण, द्वारिका प्रसाद मिश्र का साक्षात्कार, वी०पी० सिंह की वाराणसी यात्रा तथा अमेठी में राजीव के दौरों की रपट, विपक्ष की जोड़-तोड आदि सामग्री वर्तमान गरमा-गरमी का अच्छा जायजा लेने की कोशिश है। अब जब देश का सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति विवादों के घेरे में है, समस्या को ब्राह्मण-ठाकुर-विवाद के रूप में प्रस्तुत करना अति सरलीकरण कहा जायेगा। पं० कमलापति त्रिपाठी का राजीव जी को बिना मांगे आशीर्वाद देने के लिए दौड़ पड़ना उनकी आरंभ से लेकर अब तक निभायी गयी चाणक्य की भूमिका का ही नया स्वरूप है। प० उमाशंकर दीक्षित लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहे। अब जब मरने को आ गये हैं तो भी अपने को राजीवजी का सबसे बड़ा कारिंदा मानते हैं। तिकड़ी के तीसरे महापुरुष पं० द्वारिका प्रसाद मिश्र, अब प्रज्ञाचक्षु हो गये हैं लेकिन राजनीति में भी वह अब अप्रासंगिक ही हैं।

ठाकुरों का भी कमोबेश यही हाल है। राजतंत्र में बहुत दिनों तक शासक रहे लोग प्रजातंत्र में रातोरात अमीरी छोड़कर दरिद्रता का व्रत लेकर निःसंग समाजसेवक बन गये हों, ऐसा कहीं भी कभी भी देखा-सुना नहीं गया है। स्वाधीन भारत में कांग्रेस ही सबसे बड़ा राजा-रानियों का दल रहा है। इनके चक्कर में श्रमजीवियों की सदैव उपेक्षा हुई है। इसके लिए ब्राह्मण भी दोषी हैं और ठाकुर भी। पत्रकारों को तो ब्राह्मणवाद या ठाकुरवाद के चश्मे से समस्याओं को न देखकर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि इन दोनों वर्गों से दुर्बल समाज का कितना भला हो सकता है। ये उनके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं।—शिवशंकर मिश्र, संस्कृति भवन, पो०बा० २०७, राजेंद्रनगर (पूर्व), लखनऊ।

सितंबर द्वितीय अंक की आवरण कथा 'ठाकुर बनाम ब्राह्मण' विजय दत्त एवं रंजना कक्कड़ ने बड़े सटीक ढंग से प्रस्तुत कर कांग्रेस की अंदरूनी उठा-पटक को पाठकों के सम्मुख रख कर सराहनीय कदम उठाया है। इस आलेख के विस्तृत विवेचन से यह बात

मधु मिश्र

दिशाहीन आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं

१५ सितंबर, १९८७ की 'माया' में सुधा भाटिया की रपट 'खरीदिए आई०ए०एस० दूल्हा तीस लाख में' छपी थी। इस पर देश भर से प्रतिक्रिया स्वरूप अधिसंख्य पत्र प्राप्त हुए। उन पत्रों में बलरामपुर, गोंडा की कुमारी मधु मिश्रा की प्रतिक्रिया सर्वाधिक मार्मिक रही। यहां उनकी प्रतिक्रिया उन्हीं के शब्दों में प्रकाशित की जा रही है :

सुधा जी आपकी रिपोर्ट वर्तमान समाज की यथार्थता से थोड़ी हटकर है। शायद आपने दहेजरूपी सामाजिक कुरीति के बारे में केवल देखा, सुना या समझा है, स्वयं भोगा नहीं है। मैं इस संबंध में इतना जरूर कहूंगी कि इस सामाजिक विभीषिका के कारण, मेरी जिंदगी ठीक त्रिशंकु की तरह होकर रह गयी है।

मैं एम०ए० (हिंदी), बी०एड० हूं। १९८४ से मैं अध्यापन-कार्य कर रही हूं साथ ही पेंटिंग, वाटिक तथा स्वतंत्र लेखन भी करती हूं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विभिन्न प्रकार की रचनाएं भी प्रणीत करती हूं। इन कार्यों से मैं पर्याप्त धन भी अर्जित कर लेती हूं। वैसे भी मैं खाते-पीते परिवार से हूं। मेरे चार भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूं लेकिन इतनी समृद्धता के बाद भी हम लोगों को चैन नहीं है। मेरे भाई प्रतिवर्ष मेरे लिए दर्जनों लड़के देखते रहते हैं लेकिन बिकाऊ होने के कारण मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता क्योंकि खरीदे जाने वाले रिश्तों के प्रति मेरी कोई आस्था नहीं है। इसलिए मैंने अब विवाह की आवश्यकता, अपरिहार्यता एवं सार्थकता महसूस करना छोड़ दिया है। सोचती हूं, जीवन निर्वाह हेतु कुछ धन एवं अभिरुचियां ही पर्याप्त हैं और मैं उसी में अपने को लीन रखती हूं। अब तो विवाह की शाश्वतता भी तुच्छ प्रतीत होने लगी है।

कभी-कभी मैं यह भी सोचती हूं कि कहीं अपने स्वार्थ एवं आत्मतुष्टि के लिए मैं अपने माता-पिता के साथ अन्याय तो नहीं कर रही हूं जिनकी सांसे सिर्फ बेटी की मांग में सिंदूर देखने के लिए शेष हैं, न जाने उनके सांसों की लड़ियां एक अतृप्त चाह लिए कब टूट जायें ?

मैं ऐसे कितने ही माता-पिताओं को जानती हूं जिनकी रातों की नींद सिर्फ इसलिए उचट जाती है, क्योंकि उनकी बेटियां जवान, खूबसूरत और कमासू होते हुए भी अविवाहित हैं। क्या उन माता-पिताओं की आत्मा में घर कर गयी समाज के प्रति इस भयावह धारणा को बदला जा सकता है ?

सुधाजी, आप ही नहीं, पूरा समाज ही कहता है, नारी वर्ग आगे आये। आंदोलन करे लेकिन दिशाहीन आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं। विवाह न करना भी पलायनवादिता है। आपने लिखा है कि दहेज से नारी का शोषण होता है। मैं समझती हूं सिर्फ नारी ही नहीं उनके मां-बाप का भी शोषण है। बिना विवाह के भी तो इस समाज में नारी के लिए कोई स्थान नहीं। शायद आप समाज के भूखे भेड़ियों की वासनाभरी दृष्टि से वाकिफ नहीं। दूसरी तरफ, हमारे भारतीय समाज की संकीर्ण मानसिकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जहां स्त्री की पवित्रता का आकलन मात्र उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर से किया जाता है, चाहे भले ही वह मांग का सिंदूर जलती अग्नि जैसा क्यों न हो ?

हमारा युवा वर्ग समाज के प्रश्नों का उत्तर सहज ही दे सकता है, लेकिन बूढ़े मां-बाप के लिए वे उत्तर भी प्रश्नचिन्ह बन जाते हैं। अंततः इतना और कहना चाहूंगी कि आपने आई०ए०एस० दूल्हे का दाम कुछ अधिक ही बढ़ा दिया है और प्राध्यापक की दर बहुत घटा दी है। विशेषकर, बिहार में तो रु० २५,००० में एक इंटर पास दूल्हा भी मुश्किल से मिलता है फिर लेक्चरर कहां मिलेगा ? मेरे घर वाले तीन सालों से एक अदद दूल्हा ही तो तलाश रहे हैं और यही कारण है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों की दरें ज्ञात हो गयी हैं। —कुमारी मधु मिश्रा, बिहारी निवास, झारखंडी मंदिर के सामने, बलरामपुर, गोंडा।

साफ दृष्टिगोचर होती है कि यदि राजीव गांधी की पूर्ण सहमति से वयोवृद्ध राजनेता (ब्राह्मण गुट) सामंत वर्ग के नेताओं के विरुद्ध जेहाद जारी रखेंगे तो निश्चित ही यह सामंतवादी वर्ग इंका से अलग-थलग पड़ जायेगा।

राजीव गांधी के मूक आदेश पर सामंतों के खिलाफ विष वमन करने वाले ब्राह्मण राजनेता भी अपने-अपने परिजनों की उन्नति के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। पं० कमलापति त्रिपाठी चाहते हैं कि उनके लल्लू (लोकपति) को एक बार उ०प्र० का मुख्यमंत्री बना दिया जाये। महज इसी महत्वाकांक्षा को स्वीकारते हुए वह उनकी हां में हां मिला रहे हैं। दूसरी ओर राजनीति से लगभग निर्वासित से रहे पं० उमाशंकर दीक्षित भी अपनी पुत्रवधू (श्रीमती शीला दीक्षित) के उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य को संवारने हेतु बुढ़ापे में राजीव गांधी की ढाल बन कर सामने आये हैं।

हमें यह भी मानना चाहिए कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर युद्ध से अलग-थलग पड़कर यह ठाकुर लाबी के नेता चुप थोड़े ही बैठ जायेंगे क्योंकि यह बात भी सत्य है कि इन सभी सामंतवादी नेताओं का अपने क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है। इस कथा की विवेचना करने के बाद हमें राजीव गांधी की बुद्धि पर भी तरस आता है कि एक ओर तो वह सबको साथ लेकर चलने की हिमायत करते हैं फिर क्यों कुछेक नेताओं के इशारे पर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।—कु० अर्चना सक्सेना, ग्राम—नागपुर, पत्रा० भानपुर, बदायूं।

कांग्रेस के किले में सेंध

'माया' का दूसरा अंक (सितंबर) मिला। पढ़कर खुशी हुई। 'कांग्रेस के किले में सेंध' पढ़कर लगा कि वी०पी० सिंह का जनादेश बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस सिर्फ आलाकमान के निर्देश पर हर सभा को विफल करने की कोशिश कर रही है। राजर्षि की उपाधि पाने के बाद कमलापतिजी का बौखलाना वाजिब है। उन्हीं के गुट में उनका विरोधी बाजी मार ले जाये? शायद इसी लिए उसे अवैध घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पंडितजी को अब हार मान लेना चाहिए कि काशी से उनका वर्चस्व समाप्त हो गया है क्योंकि नया विश्वनाथ उनकी नगरी में प्रवेश कर गया है।—अदनान अब्बासी, निजामपुर, गोरखपुर।

बिना संजय सिंह के राजीव गांधी

३० सितंबर, १९८७ के अंक में 'अमेठी : बिना संजय सिंह के राजीव गांधी' प्रकाशित लेख के संदर्भ में मैं, कुछ कहना चाहता हूं। संजय सिंह के न रहने से कांग्रेस में राजीव गांधी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़नेवाला है। संजय सिंह जैसे व्यक्ति का कांग्रेस में न रहना कांग्रेस के लिए गौरव की बात है।

ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन-सी ईमानदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह को कुरसी पर न बैठ पाने का गम सता रहा है तो वह कह रहे हैं कि 'घर में आग लगी है, जो भी एक बाल्टी पानी लेकर आये उसका स्वागत है।'—बलदेव सिंह, मयूर विहार, नयी दिल्ली।

'माया' के १५ सितंबर, १९८७ अंक में संजय सिंह का साक्षात्कार पढ़ा। पढ़कर मालूम हुआ कि कल तक जो प्रधानमंत्री की वकालत करते हुए नहीं थकता था, वही व्यक्ति राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को भी तैयार है। मात्र इसलिए कि राजीव गांधी ने उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। काश! राजीवजी उनकी हसरत पूरी कर देते तो शायद संजय सिंह की नजर में वी०पी० सिंह ही देश के सबसे बड़े भ्रष्ट होते।—मो० रसीद, शिवगढ़, रायबरेली।

संजय सिंह की बगावत

मैंने माया का १५ सितंबर, १९८७ अंक पढ़ा। आवरण कथा के अंतर्गत विश्वनाथ-अरुण नेहरू-आरिफ की तिकड़ी को अनावश्यक महत्व दिया गया है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इस तिकड़ी की गिरती जा रही छवि को निखारने का असफल प्रयास किया गया है।

विशेष रिपोर्ट में 'संजय सिंह की बगावत' शीर्षक में डा० संजय सिंह के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश का विवरण काफी रोचक है।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को चुनौती देना संजय सिंह का 'हाथ के पंखे से आंधी पैदा करके सूर्य को बुझाने' का दिवा-स्वप्न है।—वीरेंद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, बहराइच।

वी०पी० सिंह प्रधानमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं...।

—द्वारिका प्रसाद मिश्र, रविवार से

यह संभव ही नहीं कि मैं ऐसे व्यक्ति (विश्वनाथ प्रताप सिंह) का नेतृत्व स्वीकार कर लूं।

—चंद्रशेखर, वी०पी० सिंह के बारे में, टेलीग्राफ से

प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यही भ्रष्टाचार की जड़ है।

—मोरारजी देसाई, इंडियन एक्सप्रेस से

वी०पी० सिंह विभीषण हैं। जो व्यक्ति रावण के दल की जय-जयकार करता रहा हो, उसका इसके सिवा और क्या नाम हो सकता है?

—बहुगुणा

अरुण नेहरू उतने ही स्वतंत्र हैं, जितना मैं। वह मेरे अधीन नहीं हैं।

—वी०पी० सिंह, एशिया वीक से

द्वारिका प्रसाद मिश्र

लोगों की आंखों में रोने तक के लिए पानी नहीं है।

—एन०टी० रामाराव, आंध्र प्रदेश में सूखे पर

राष्ट्रपति शासन से पूर्व आतंकवादी कार्यवाही करते थे और हम जवाब देते थे। अब हम कार्यवाही कर रहे हैं और वे जवाब दे रहे हैं।

—पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय

महेंद्र सिंह टिकैत

वह (वीर बहादुर सिंह) मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। दूसरी ओर, दोनों (राजीव गांधी व विश्वनाथ प्रताप सिंह) चोर हैं। एक बड़ा चोर। एक छोटा चोर।

—किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत

इतनी महान बेटी का बाप होने पर मुझे गर्व है।

—सती 'रूप कंवर' के पिता बाल सिंह

आपातकाल को छोड़कर उनकी मां (इंदिरा गांधी) का प्रेस से व्यवहार बहुत बुरा नहीं था।

—रामनाथ गोयनका, इंडिया टुडे से

विनोद खन्ना

इस बार हमारा भी प्रदर्शन अच्छा होगा।

—आस्ट्रेलियाई टीम के मैनेजर एलेन कोफ्रेंट, आज से

बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में हम दूसरों की तुलना में इक्कीस ठहरते हैं, बस हमारी गेंदबाजी ही लचर है।

—दिलीप वेंगसरकर, चौथी दुनिया से

मैंने हमेशा पैसे को महत्व दिया...।

—विनोद खन्ना, माधुरी से

रामखिलावन बनारसी पानवाला भी ले आया बोफोर्स से चिट्ठी

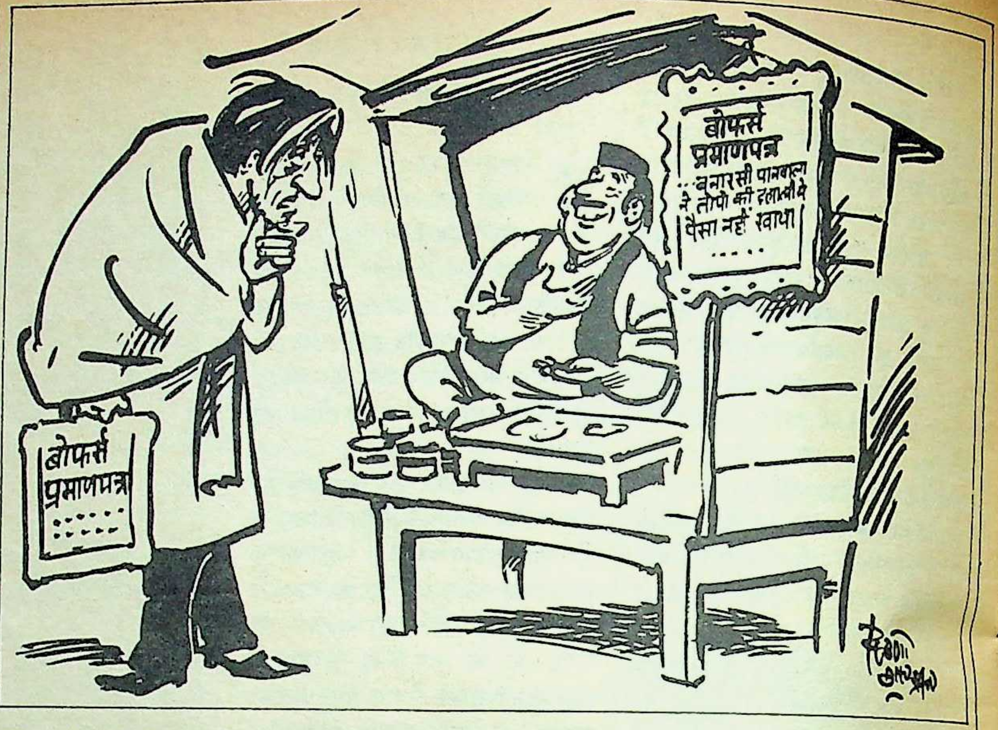

जब अमिताभ बच्चन ने बोफोर्स कंपनी से आये लिफाफे पर लिपिस्टिक लगे अपने ओठों से गहरा चुंबन लिया, तो जया ने लपक कर लिफाफा छीन लिया— "यह क्या पागल हो गये हो। दिल्ली दरबार जब यह लिफाफा देखेंगे, तो क्या सोचेंगे ?" वह अपने पल्लू से लिफाफे पर लगी लिपिस्टिक को पोंछने लगीं। उसी समय वसंत विहार में अमिताभ की कोठी के बाहर बैठने वाला, बनारसी पान वाला आ गया। अमिताभ को बनारसी पान देने के बाद वह संकोची मन लिये, ठिठक कर खड़ा हो गया। पान मुंह में लेकर अमिताभ ने पूछा, "का बात है बनारसी भैया ! कुछ कहा चाहित हो ?" संकोच को अपने कुरते की जेब में डालते बनारसी पानवाले ने तुरंत एक लिफाफा अमिताभ बच्चन के सामने बढ़ा दिया— "मेरे पास भी यह बोफोर्सी लिफाफा आ गया। लिखा है कि राम खिलावन बनारसी पानवाला ने तोपों की दलाली में कोई पैसा नहीं खाया है। आप दिल्ली दरबार जा रहे हैं। हमारी चिट्ठी भी दरबार को दिखा देना।" जया 'बावर्ची' स्टाइल में बरसने को हुई, तो अमिताभ ने 'मर्द' स्टाइल में उनको पीछे करते हुए कहा, "रुको जया। मैं इस साले से निपटता हूं।" राम खिलावन बनारसी पानवाले की देखा-देखी अमिताभ बच्चन के एक दर्जन से ऊपर घरेलू नौकर और ड्राइवर भी अपना-अपना बोफोर्सी लिफाफा लेकर आगे बढ़े थे। लेकिन जब उनको अमिताभ बच्चन के तेवर दिखायी पड़े, तो वे अपना-अपना बोफोर्सी लिफाफा जेब में रखकर गधे के सींगों की तरह अदृश्य हो गये।

अमिताभ बच्चन ने गिड़गिड़ाते और हाथ-पैर जोड़ते बनारसी पान वाले को अपने कद की ऊंचाई तक उठाकर कोठी के बाहर फेंक दिया। वह धड़ाम से अपनी पान की दुकान पर जा गिरा। उसकी जेब से लिफाफे की चिट्ठी निकल कर दुकान के शीशे पर चिपक गयी, जिस पर लिखा था— "बोफोर्स कंपनी ने राम खिलावन बनारसी पानवाले को तोपों की दलाली का कोई पैसा नहीं दिया है।" राम खिलावन धूल झाड़ कर जैसे ही दुकान की गद्दी पर बैठने को हुआ, सामने की कोठी से अमिताभ बोफोर्सी ईमानदारी का टीका माथे पर लगा कर, दिल्ली दरबार से मिलने के लिए निकले, तो उन पर आगे-पीछे, नीचे-ऊपर बंबइया सिक्योरिटी चिपक ली। वह कार में बैठने को हुए ही थे कि पीछे से जया चिल्ला उठी, "रुको-रुको। दिल्ली दरबार से फोन आया है। कहा जा रहा है कि मिलने जाने से पहले अपनी बोफोर्स चिट्ठी अखबारों में छपवाओ। दिल्ली दरबार 'थ्रू' न्यूजपेपर तुम्हारी ईमानदारी की जानकारी लेगा।" अमिताभ की कार 'बैक गियर' में आ गयी। कार से उतरते हुए अमिताभ बच्चन जया पर बरस पड़े, "चुप भी रहोगी या चिल्लाती रहोगी। कहां है वह अपना खबरची दलाल उसे फौरन बुलाओ। लाखों अखबार वालों के नाम पर खा गया। बड़ी डींगे मारता है कि जो चाहो अखबारों में छपवाओ। बी०बी०सी० से लेकर दिल्ली तक के सारे अखबार वाले उसके तलुए चाटते हैं।" अमिताभ लंबी टांग करके सोफे पर बिछ गये। मय जया के सारे नौकर-चाकर खबरचियों के दलाल की ढुंढ़ाई करने लगे। जया ने देख लिया। वह खबरचियों की दलाली से खरीदी गयी अपनी नयी मारुति के अंदर 'इम्पोर्टेड दारू' की बोतलें भर रहा था। जया के चिल्लाने पर बंबइया सिक्योरिटी के आधा दर्जन गार्डों ने उसे दबोच लिया।

जब उसको गार्ड्स रस्सी में कसकर अमिताभ बच्चन के सामने लाये, तो उसके दोनों हाथों में जानी वाकर की बोतलें गाना गा रही थीं— "सिर जो तेरा चकराये या दिल डूबा जाये...।" अमिताभ बच्चन ने भभकी देते हुए अपने खबरची दलाल से पूछा, "क्यों बे, कहां ले जा रहा था, ये विदेशी दारू की बोतलें। तुझे पता है कि मेरे बाप इन दारू की बोतलों के लिए अपनी 'मधुशाला' में कितने झूमे हैं। तू इनको इतनी आसानी से खबरचियों की दलाली के नाम पर रोज पार कर देता है। रख इनको इधर और खड़ा हो सीधा।" खबरची दलाल हाथ की जानी वाकर को जमीन पर रख कर जैसे ही सीधा खड़ा हुआ, तो कुरते के नीचे, पैजामे के अंदर की जानी वाकरों ने नीचे खिसकना शुरू कर दिया। अमिताभ ने भांप लिया— "पैजामे में जो बोतलें छुपा रखी हैं, उनको भी निकाल कर बाहर रख।" खबरची दलाल ने आहिस्ता से उनको भी निकाल कर रख दिया, तो अमिताभ ने 'बोफोर्सी लिफाफा' उसके सामने करते हुए कहा, "देख, यह चिट्ठी सारे अखबारों में छपनी है। तू कहता है कि तूने बहुत माल-पानी खबरचियों के ऊपर लगाया है।" अमिताभ के खबरची दलाल ने बोफोर्सी लिफाफा हाथ में थामने के बाद एक टकटकी से जमीन पर जानी वाकरों को देखना शुरू कर दिया। अमिताभ ने सोफे से उठते हुए कहा, "ले जा, ले जा। मगर तू तो पीने के नाम पर केवल सूंघता है। क्या इनको कहीं बेच तो नहीं देता है ?" खबरची दलाल ने ही... ही... करके जानी वाकरों को उठा लिया— "आज कल विदेशी दारू दिल्ली में काफी महंगी बिक रही है।"

दिल्ली दरबार जब इतवार की शाम को अपने महरौली के फार्म हाउस पर दोपहरिया काटकर सतीश शर्मा के फार्म हाउस में इटेलियन टाइल्स के तरण-ताल का मौका-मुआयना करके लौटे, तो 'इनर सर्किट टी०वी०' पर काली बिल्लियों (सुरक्षा गार्डों) को ड्यूटी पर मटर-गश्ती करते हुए देखा, तो आपे से बाहर हो गये। तुरंत बूटा सिंह को फोन हुआ, तो वह अपनी नंगी कृपाण लेकर आन्तरिक सुरक्षा के आक्सफोर्डी चिदम्बरम पर चढ़ बैठे। चिदम्बरम को अकसर गुस्सा नहीं आता है। लेकिन उस इतवार उन्होंने सांबर में मिर्च कुछ

ज्यादा खा ली थी; इसलिए कुछ कड़ुआ बोलने लगे। बूटा सिंह से जब कुछ न बना, तो अपनी कृपाण गृह मंत्रालय की खूंटी पर टांगते हुए बोले— "ठीक है। जब मेरे सुरक्षा गार्ड की बीवी तक को तुम लोग गायब कराये दे रहे हो, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं या न करूं।" वह रुंआंसे से दिल्ली दरबार में चिदम्बरम की शिकायत लेकर जब पहुंचे, तो वहां सोफों पर इंकाई लाशें बिछी हुई थीं। नवल किशोर शर्मा ने जब मुंह फाड़ कर जंभाई ली, तो बूटा सिंह ने पूछा— "यहां कब से बिछे हुए हो।" शर्मा जी दूसरी बार मुंह फाड़ कर सोफे पर सीधे हो लिये। बगल में बैठने का इशारा करते हुए नवल किशोर शर्मा ने कहा— "आओ बैठो बूटा। सुबह से दिल्ली दरबार के दीदार का इंतजार करते-करते रात के ११ बज गये। सुना है कि दिल्ली दरबार डिनर लेकर वीडियो पर कोई फड़कती हुई फिल्म देखने में मशगूल हैं। अरे यह तो राज-काज है और सुनाओ कैसा चल रहा है!" बूटा और नवल किशोर की बात सुनकर एक दूसरे सोफे पर बिछे आर०एल० भाटिया ने करवट ली, तो उनकी टांग भगवत झा आजाद की खोपड़ी से टकरायी। आजादजी तुरंत उठ बैठे— "अबे भाटिये, क्या तेरी शामत आ गयी है। आजाद का लबादा तो मैंने ओढ़ रखा है, लेकिन मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा 'झा' हूं।" भाटिया क्षमा-याचना की मुद्रा में आये कि उसके पहले डबल सोफे पर बिछे सीताराम केसरी उठकर पद्मासन में आ गये— "हमारे बिहार में अगर किसी झा के गलती से लात लग जाये, तो उस पाप से उऋण होने के लिए एक भरपूर लात उस झा को लगानी पड़ती है। भाटियाजी आपको मेरे खयाल से पाप से तुरंत ही उऋण हो जाना चाहिए।" भगवत झा आजाद केसरीजी पर लपकें कि उसके पहले वह सोफे पर से कूद कर दरवाजे के बाहर हो लिये। लेकिन वह बाहर से आते हुए जी०के० मूपनार की लुंगी से टकरा कर गिर गये। मूपनार ने केसरीजी को फौरन थाम लिया। एंथोनी ने जैसे ही देखा कि मूंपनार आ रहे हैं, वह अपनी लुंगी संभाल कर सोफे से उठ लिये। मूपनार अंदर से ताक-झांक करके लौटे थे। वह गुमसुम एक सिंगल सोफे पर लुढ़क लिये। जब उनको इंकाई लाशों ने घेर कर कुरेदना शुरू किया, तो वह मद्रासी पान की गिलौरी दबाकर जबड़ा चलाने लगे— "दिल्ली दरबार को वीडियो पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नवीनतम फिल्म 'करामात इंकाई महा-मंत्रियों' की दिखायी जा रही है। यह गुलाम-नबी आजाद बहुत डबल है। बगैर फिल्म देखे उसने फिल्म का रिव्यू करके दिल्ली दरबार को पकड़ा दिया है। गुलाम कहता है कि 'करामात इंकाई महामंत्रियों' की फिल्म से सभी महामंत्रियों का रोल बहुत घटिया है। दिल्ली दरबार फिल्म कम देख रहा है और गुलाम नबी का 'रिव्यू' ज्यादा पढ़ रहा है। उसका चेहरा लाल-पीला-नीला हो रहा है।" भगवत झा आजाद ने नथुनों से फुंकारे मारते हुए कहा— "कहां है वह गुलाम नबी। आज उसे बता दूंगा कि उससे बड़ा आजाद मैं हूं।" रघुनंदन लाल भाटिया ने भगवत झा को समझाते हुए कहा— "झाजी गुस्सा थूक दो। हो सकता है कि इसमें भी हमारी कोई भलाई हो। दिल्ली दरबार को अपनी सरकार में मंत्री बनाने के लिए कुछ निकम्मे लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को तो निकम्मेपन का सार्टीफिकेट मिल रहा है।" भगवत झा आजाद के चेहरे पर हजार वाल्ट का बल्ब जल गया। वह मंत्रिमंडलीय कुरसी की चकाचौंध में उड़ने-गिरने लगे। मंत्रिमंडलीय कुरसी का बल्ब अन्य लोगों के चेहरे पर जले कि उसके पहले जार्ज दनदनाते हुए आये और उन्होंने इशारा किया कि दिल्ली दरबार के 'अर्धरात्रि दरबार' में सभी लोग हाजिर हों। इंकाई लाशें आहिस्ता-आहिस्ता उठीं और अपनी मंद भुतई चाल से दिल्ली दरबार में पहुंच गयीं।

दिल्ली दरबार के 'पोस्ट इको वायल चैनल' पर उद्घोषणा हो चुकी थी कि सभी इंकाई महामंत्री अपना अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने निकम्मेपन की परीक्षा अव्वल नम्बरों से उत्तीर्ण कर ली है। अब दूसरा बैच निकम्मेपन की परीक्षा के लिए प्रवेश लेगा।

> ***दिल्ली दरबार पंचम में गरजे— "यह कौन है?" अमिताभ बढ़कर उसका मुंह दबोचें कि उसके पहले उसने बोलना शुरू कर दिया— "सरकार, मैं रामखिलावन बनारसी पानवाला हूं। हुज़ूर मेरे पास भी बोफोर्सी चिट्ठी आ गयी है कि मैंने तोपों की दलाली में कोई पैसा नहीं खाया है।***

इंकाई महामंत्रियों के इस्तीफों के बाद दिल्ली दरबार की 'अर्धरात्रि सभा' विसर्जित होने ही वाली थी कि गुलाम नबी आजाद बदहवासी के आलम में भागते हुए आ गिरे। दिल्ली दरबार स्तब्ध रह गये। वह पंचम में चीखे— "गुलाम, यह तेरा थोबड़ा किंसने बिगाड़ दिया है!" गुलाम नबी ने अपनी आजादी दिल्ली दरबार के चरणों पर रखते हुए रोना शुरू कर दिया— "हुज़ूर! आपके कश्मीरी यार फारुख अब्दुल्ला ने बहुत मारा है। कहता है कि कश्मीर की वादियों में घुसने की कोशिश की, तो चिनार के पेड़ पर उलटा लटकवा दूंगा। सारे समझौते तोड़कर दिल्ली दरबार की भी ऐसी तैसी कर दूंगा।" दिल्ली दरबार मंद-मंद मुस्कराये— "यार का हक बनता है, मेरे गुलाम का थोबड़ा बिगाड़ देने का। अगर फारूख नहीं चाहता, तो मैं तुझे कश्मीर की वादियों में नहीं भेजूंगा। तुझे मैं २४, अकबर रोड पर तैनात किये देता हूं। चल उठ, मुंह धोकर आ। तेरा थोबड़ा देखा नहीं जा रहा है।" दिल्ली दरबार उठने को थी तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी "टन...टन...टन..." करते हुए दिल्ली दरबार में अमिताभ बच्चन अपने 'खबरची दलाल' को लेकर घुस आये। टनटनाती गाड़ी से छलांग मारकर अमिताभ दिल्ली दरबार के कंधे पर जा गिरे, तो वह 'उई' करके चिल्ला पड़े— "अमि तुम्हारा प्रवेश तो मैंने वर्जित कर रखा है। तुम दरबार में कैसे घुस आये?" अमिताभ ने दिल्ली दरबार के कंधे पर मालिश करते हुए कहा— "यार तुम तो जया से डींग मार रहे थे कि अब तुम्हारे कंधे बहुत मजबूत हो गये हैं। वे हर वार सह सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वे मेरी फिल्मी दुल्लती से कराह उठे।" दिल्ली दरबार ने अमिताभ के हाथ को झिटकते हुए कहा— "बकवास मत किया करो। घर की बात दरबार में 'डिसकस' नहीं होती।" इसी बीच अमिताभ के 'खबरची दलाल' ने दरबारियों के बीच 'बोफोर्सी खत' की छपी खबरों के अखबार को बांटना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि "अमिताभ बच्चन ने तोपों की दलाली का पैसा नहीं खाया है।"

दिल्ली दरबार को अखबार पढ़ते दरबारियों से बहुत सतोष मिला। वह उचक-उचक कर बोलने लगे— "मैं पहले ही कहता था कि मेरा अमिताभ अनाड़ी नहीं है। माल खाकर डकार न लेने का इसने काफी 'रिहर्सल' कर रखा है।" अमिताभ बच्चन ठुमका लगाकर जब "खै के पान बनारस वाला..." शुरू हुए, तो अचानक दिल्ली दरबार में खतरे का सायरन बज उठा। मय दिल्ली दरबार के सारे दरबारी अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गये। चारों ओर सायरन की आवाज ने आतंक पैदा कर दिया। एक सहमा-सा आदमी हाथ में पान का एक बीड़ा लिये इधर-उधर देखता हुआ अंदर आ गया। दरबार के फर्श पर औंधे लेटे अमिताभ ने उसे फौरन पहचान कर आहिस्ता से उठना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन की देखा-देखी मय दिल्ली दरबार के सब लोग उठ कर अपने-अपने ठिकाने पर आ गये। दिल्ली दरबार पंचम में गरजे— "यह कौन है?" अमिताभ बढ़ कर उसका मुंह दबोचे कि उसके पहले उसने बोलना शुरू कर दिया— "सरकार, मैं राम खिलावन बनारसी पानवाला हूं। हुज़ूर मेरे पास भी बोफोर्सी चिट्ठी आ गयी है कि मैंने तोपों की दलाली में कोई पैसा नहीं खाया है। सरकार, मैंने अमिताभ भैया से कहा था कि मेरी बोफोर्सी चिट्ठी भी दिल्ली दरबार में दिखा दी जाये कि मैंने कोई दलाली नहीं खायी है। लेकिन अमिताभ भैया ने मुझे दुलत्ती मार कर घर से बाहर फेंक दिया। सरकार, आपके लिए बनारसी पान लाया हूं... सरकार मैंने कभी भी दलाली का पैसा नहीं खाया... सरकार मैं बिलकुल निर्दोष हूं ... हम लोग करोड़ों की रकम लेकर क्या करेंगे...।" दिल्ली दरबार के इशारे पर दरबार की सारी बत्तियां धीरे-धीरे गुल कर दी गयीं। पूरा दरबार निबिड़ अंधकार में डूब गया। हर तरफ मरघट जैसी गहन खामोशी छा गयी। पूरे दरबार में केवल राम खिलावन की ही आवाज रह गयी— "सरकार मैंने बोफोर्स से तोपों की दलाली में कोई पैसा नहीं खाया। आप चाहें, तो चिट्ठी देख लें। मैं गंगा कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने और मेरे परिवार ने कोई दलाली नहीं खायी..."

—दरबारी लाल

जो टीम पिछली दो विश्व कप प्रतियोगिताओं में मात्र एक मैच जीत पायी हो, वह चैंपियन बन जायेगी—यह सपना नहीं तो और क्या है। मगर अचरज की बात है कि २२ जून, १९८३ को सारे देश का यह सपना साकार हो गया और भारत विश्व चैंपियन बन गया। अप्रत्याशित होने के कारण यह जीत और मधुर थी। भारत ने केवल प्रुडेंशियल विश्व कप ही नहीं जीता, बल्कि एशिया कप, राथमैंस कप और 'बेंसन ऐंड हेजेज वर्ल्ड चैंपियनशिप' जीतने का गौरव भी प्राप्त किया। विजेता होने की हैसियत और प्रुडेंशियल कप से दुगनी पुरस्कार राशि की व्यवस्था कर लेने की बदौलत चौथे विश्व कप का आयोजन-स्थल इंग्लैंड से बदलवाने में भी भारत को सफलता मिली। यों तो भारत और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में दोनों का याराना है। इसीलिए दोनों रिलायंस कप को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए सहमत हुए। यह सहमति दुनिया के लिए एक सबक है—खासकर दक्षिण और उत्तर कोरिया के लिए जो आगामी ओलंपिक्स को लेकर झगड़ रहे हैं।

आयोजन करने के लिहाज से भारत कई मामलों में अव्वल है। भारत पहला देश है, जिसने १९५० में पहले एशियायी खेल आयोजित किये और बंबई में विश्व टेबिल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित करनेवाला प्रथम एशियायी देश भी भारत है। बिलियर्ड और स्नूकर की विश्व प्रतियोगिताओं, दो एशियाड और तीन विश्व टेबिल टेनिस प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय खेलों की सफल व्यवस्था की है। लेकिन विश्व क्रिकेट कप का इंतजाम करना एक कठिन चुनौती है। अन्य खेलों की अपेक्षा, रिलायंस कप के मुकाबले भारत के १४ शहरों में होंगे—पाकिस्तान में खेले जाने वाले सात मैच तो अलग हैं ही। काम तो बड़ा भारी है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों और क्रिकेट बोर्डों के सद्भाव एवं सहयोग को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रिलायंस कप का आयोजन सफल होगा।

यद्यपि क्रिकेट के कुछ चोटी के खिलाड़ियों की अनुपस्थिति अखरेगी, लेकिन फिर भी खेल की दृष्टि से रिलायंस कप स्मरणीय होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस आयोजन से क्रिकेट को अपार प्रोत्साहन मिलेगा और भारत के लोगों को अपनी धरती पर आठ टीमों में से सात टीमों के प्रदर्शन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

रिलायंस कप के प्रति आम उत्साह का ही परिणाम है 'माया' का रिलायंस कप विशेषांक। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ियों, अंपायरों, प्रतिष्ठित पत्रकारों, कमेंटेटरों और सांख्यिकी विशेषज्ञों के एकजुट प्रयास से यह विशेष अंक तैयार हुआ है। यदि यह अंक आपको पसंद आया, तो मैं समझूंगा कि 'माया' की टीम के साथ मैंने जो कार्य किया है, वह सार्थक हो गया।

शुभकामनाओं के साथ,

—नरोत्तम पुरी
रिलायंस कप सामग्री के
सलाहकार संपादक

छाया:
सुनील सक्सेना

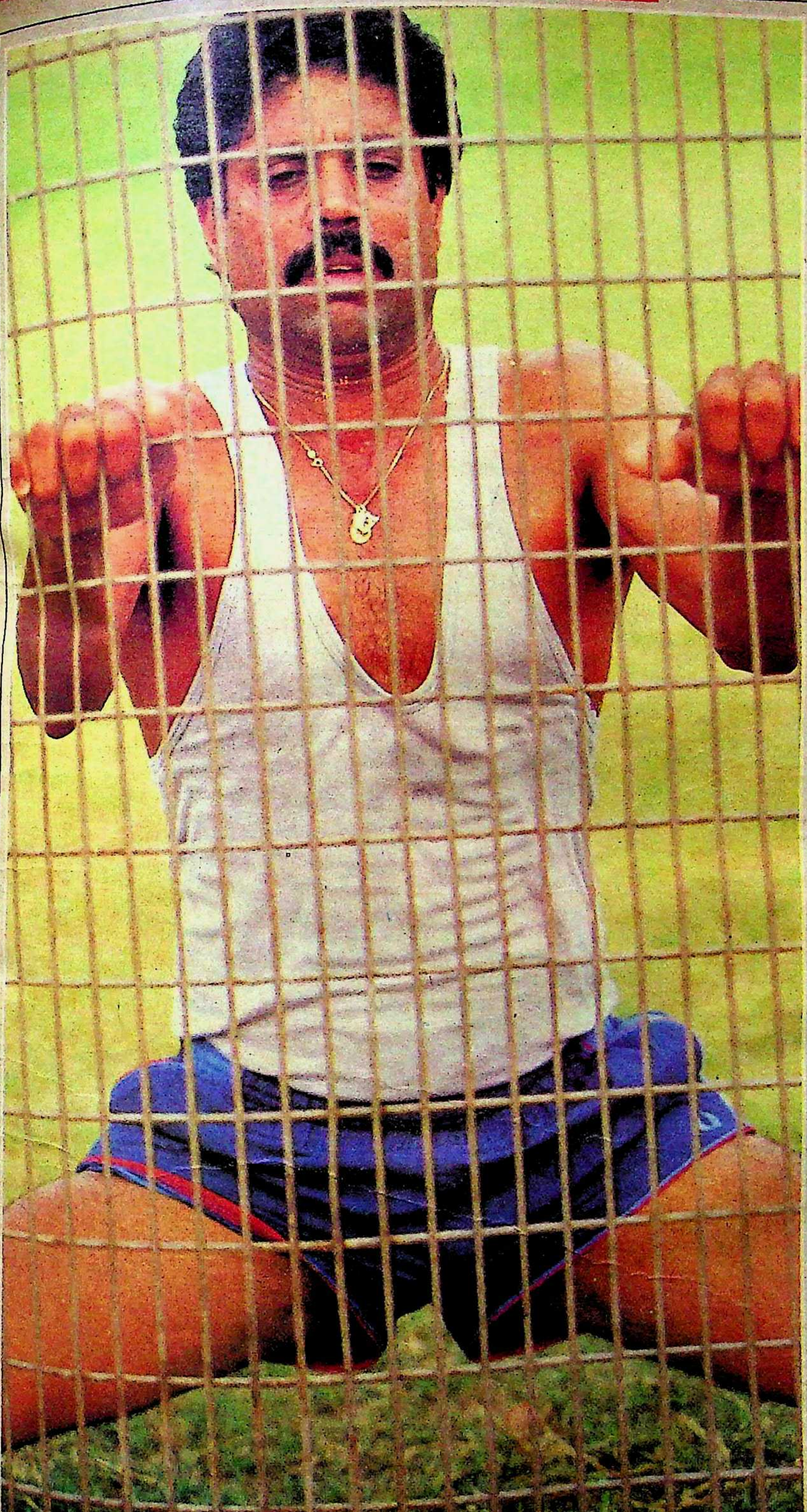

राष्ट्रीय खेल संस्थानः दिल्ली में आयोजित तीन सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर के दौरान कसरत करते हुए कपिल देव। रिलायंस कप, कपिल की नेतृत्व क्षमता की अग्नि परीक्षा साबित होगा। (बायें)

रिलायंस कप में ढेरों रिकार्ड बनाने वाले सुनील गावस्कर के कुछ और नये रिकार्डों का इंतजार रहेगा। लार्ड्स में शतक बनाने के बाद टेस्ट क्रिकेट से उनकी विदायी शानदार रही थी। देखना है एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा वह किस अंदाज में कहते हैं। गावस्कर के साथ कपिल देव। (नीचे)

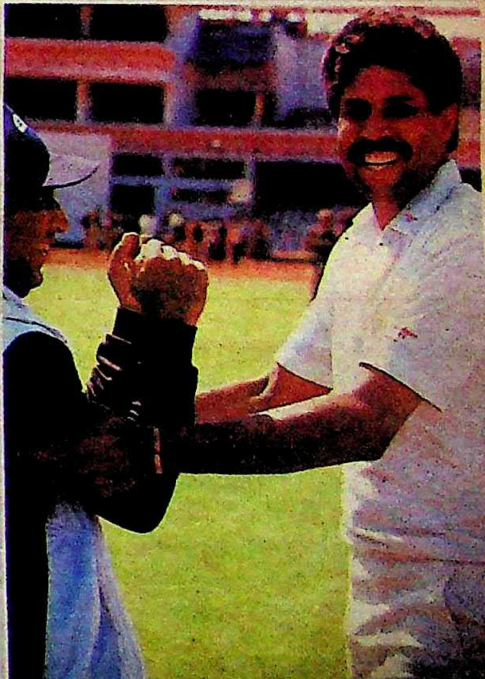

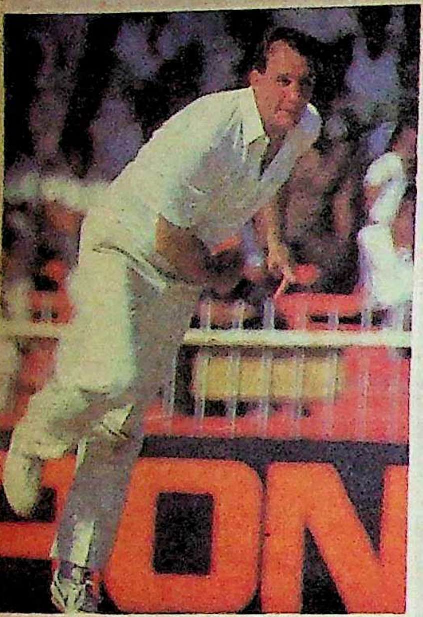

कई सितारा खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद जान एंबुरी ने इसी साल शारजाह कप इंग्लैंड की झोली में डाल दिया था। एंबुरी की स्पिन गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी इंग्लैंड की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। (बायें)

स्पिन गेंदबाजी में ब्रूस रीड को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पायी है, मगर भारत की निर्जीव पिचों पर वह भी कहर बरपा सकते हैं। (बायें नीचे)

दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट संबंधों के लिए चर्चित ग्राहम गूच इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ होंगे। डेविड गावर और इयान बाथम की अनुपस्थिति से भी उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गयी है। (दायें नीचे)

छाया : प्रदीप मंधानी

ाया : सुनील सक्सेना

Brooke Bonds
SS
TURBO

छाया: बिंदु अरोड़ा

फटाफट क्रिकेट में धुआंधार बल्लेबाजी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पाकिस्तान के सलीम मलिक उन गिने-चुने खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी आतिशी बल्लेबाजी से मैच का रुख ही बदल देते हैं। (बायें)

इमरान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने क्रिकेट की कई बुलंदियों को चूमा है, लेकिन पिछले दो विश्व कप के सेमी फाइनल तक पहुंचने के बाद भी कप जीतने की उसकी हसरत पूरी नहीं हो सकी है। क्या इमरान पाक क्रिकेट प्रेमियों की यह इच्छा पूरी कर पायेंगे? (नीचे)

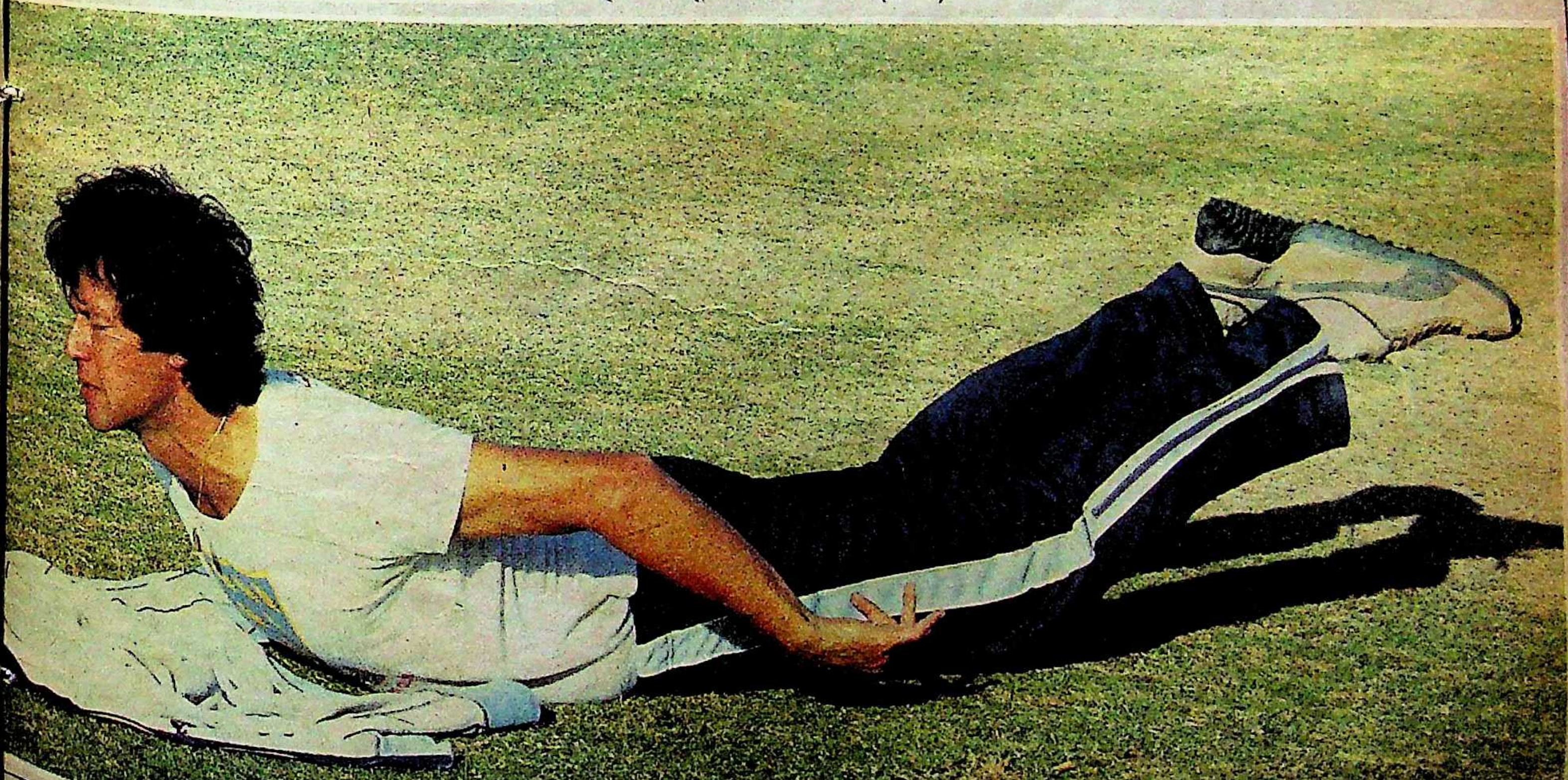

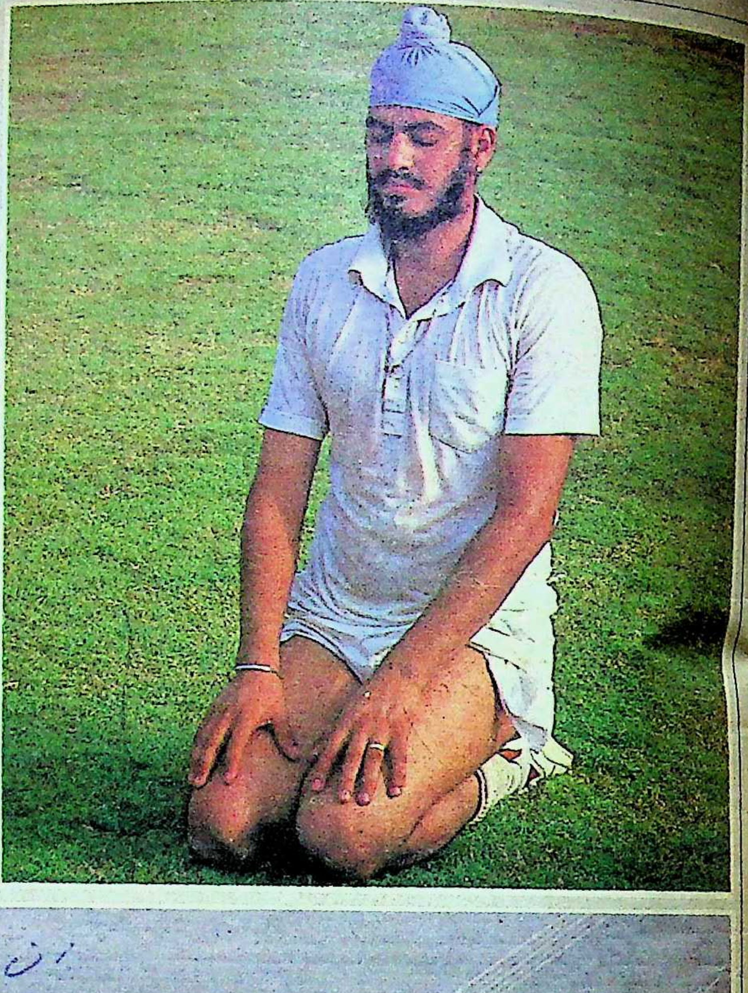

मनिंदर को मिल रही लगातार सफलताओं के बाद चयनकर्ताओं का विश्वास स्पिन गेंदबाजी पर एक बार फिर जमा है। रिलायंस कप में भारतीय गेंदबाजी का मुख्य दारोमदार मनिंदर के कंधों पर होगा। (दायें)

अभ्यास के लिए पर्याप्त समय न मिल पाने के बावजूद ३० सितंबर को रिलायंस कप उद्‌घाटन मैच में भारत का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा। खास तौर पर क्षेत्ररक्षण में काफी चुस्ती दिखायी दी। रिलायंस कप में भारत की हार और जीत बहुत कुछ क्षेत्ररक्षण के स्तर पर निर्भर करेगी। (नीचे)

सबसे महंगी क्रिकेट प्रतियोगिता

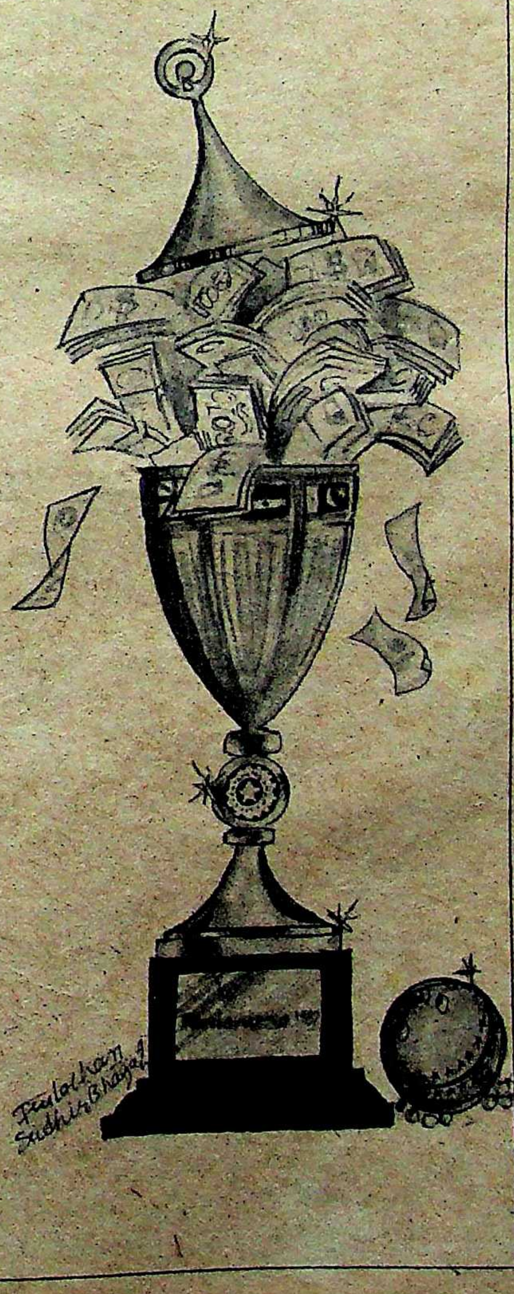

भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रिलायंस विश्व कप हर लिहाज से क्रिकेट की अन्य प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च है। इंग्लैंड के बाहर पहली बार होने जा रहा, यह विश्व कप सबसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जायेगा, साथ ही यह अब तक का सबसे खर्चीला विश्व कप भी होगा। जब पहले-पहल भारत ने इस प्रतियोगिता को आयोजित करने की पेशकश की थी, तो यह संदेह और आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था, कि क्या भारत इसके लिए आवश्यक करीब १८ लाख पौंड (३०.२६ करोड़ रुपए) की विशाल राशि जुटा पायेगा ? मगर भारत-पाक संयुक्त प्रबंध समिति (आई०पी०जे०एम०सी०) के अध्यक्ष एन०के०पी० साल्वे के अनुसार, "चूंकि भारत में क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए इतने धन की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा।"

लगभग १८ लाख पौंड की विदेशी मुद्रा जुटा पाना भी कोई हंसी-खेल नहीं था, मगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने के कारण यह काम भी सरलता से पूरा हो गया। विश्व कप का प्रायोजक बनने के लिए २.२ करोड़ रुपए की फीस भरनी थी। यह राशि रिलायंस इंडस्ट्री से प्राप्त की गयी। बाकी बची राशि विभिन्न क्रिकेट संगठनों से मिली गारंटी मनी से एकत्र की गयी (१९८३ में प्रुडेंशियल कप का प्रायोजक बनने के लिए बीमा कंपनी को केवल ८० लाख रुपए फीस के रूप में देने पड़े थे)। आई०पी०जे०एम०सी० के संयोजक आई०एस० बिन्द्रा के अनुसार, "किस मद पर कितनी राशि खर्च करनी है, इसका बजट पहले ही तैयार कर लिया गया है।"

रिलायंस विश्व कप जीतनेवाली टीम को दी जाने वाली ट्राफी के निर्माण पर ही करीब छह लाख रुपए खर्च किये गये हैं। सोने का पानी चढ़ी इस ट्राफी की डिजाइन इंग्लैंड की महारानी के जेवर तैयार करनेवाली कंपनी 'गैरेड्स' ने तैयार की है। ट्राफी में एक हीरा लगा हुआ है और भाग लेने वाले आठ देशों के झंडे बने हुए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली हर टीम को ८ लाख रुपए की 'गारंटी मनी' दी जायेगी।

विश्व कप जीतनेवाली टीम को मिलनेवाली पुरस्कार राशि भी बढ़ी है। अब विजेता टीम को ६.२ लाख रुपए मिलेंगे। उपविजेता टीम को मिलनेवाली इनाम राशि २.५० लाख रुपए होगी। इसके अलावा प्रारंभिक मैचों में विजय प्राप्त करनेवाली टीम को ३० हजार रुपए हर विजयी मैच के हिसाब से दिये जायेंगे। सेमीफाइनल में हारनेवाली टीमों को १.२५ लाख रुपए मिलेंगे। २७ मैचों में 'मैन आफ द मैच' अवार्ड के लिए ६.२ लाख रुपए की राशि रखी गयी है। यह तो हुई पुरस्कारस्वरूप दी जानेवाली राशि। इसके अलावा यात्रा, रहने और खाने के प्रबंध और स्टेडियम के जीर्णोद्धार पर भारी राशि खर्च हुई है और होगी। खिलाड़ियों की यात्रा और उनके रहने-खाने पर ही भारत को ४ करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्टेडियमों की हालत सुधारने में १२ करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं, जिसमें से ७.५ करोड़ रुपए कलकत्ता, ४५ लाख रुपए चंडीगढ़, २० लाख रुपए अहमदाबाद और १५ लाख रुपए बंबई में खर्च हुए हैं।

विश्व कप में निर्णायकों के लिए भी तगड़े पारिश्रमिक की व्यवस्था की गयी है। संयोजक बिन्द्रा के अनुसार, "२७ मैचों में केवल अंपायरों को ३.३५ लाख रुपए बतौर फीस के दिये जायेंगे। इसके अलावा उनके रहने-खाने और यात्रा पर जो खर्च होगा, सो अलग। हर प्रारंभिक मैच में (२४ प्रारंभिक मैच होंगे) प्रत्येक अंपायर को ६३०० रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल मैच (दो) में यही पारिश्रमिक बढ़कर ८,५०० रुपए और फाइनल में १०,५०० रुपए हो जायेंगे।

संयुक्त समिति की आय का एक स्रोत भाग लेनेवाली टीमों पर होनेवाले जुर्माने की राशि भी होगी। श्री साल्वे के अनुसार ८० लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक की राशि इसके जरिये समिति को मिलने की उम्मीद है। कोई टीम किसी भी तरह से समय नष्ट करने की कोशिश न करने पाये, इसलिए भारी जुर्माना तय किया गया है। उदाहरण के लिए यदि फाइनल में कोई टीम नियत ओवर से एक ओवर कम फेंकती हैं, तो उस पर १२,००० रुपए जुर्माना ठोंक दिया जायेगा और यदि वह इससे भी कम ओवर फेंकती है, तो उक्त राशि में ६,००० रुपए प्रति ओवर की दर से जुर्माना किया जायेगा। जुर्माने की राशि हर मैच के बाद टीम के खाते में जुड़ती जायेगी, जो बाद में उसकी पुरस्कार राशि से काट ली जायेगी। यदि जुर्माने की राशि पुरस्कार राशि से भी ज्यादा निकली, तो टीम को दी जाने वाली गारंटी मनी से जुर्माना वसूल किया जायेगा। केवल 'मैन आफ द मैच' के पुरस्कार को सभी विवादों से मुक्त रखा गया है।

सभी १४ स्टेडियमों के अंदर विज्ञापनों के अधिकार रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीद लिये हैं। सभी स्टेडियमों में ४५० फुट की जगह रिलायंस कंपनी ने अपने उत्पादों के लिए सुरक्षित रखी है। बाकी जगह के लिए उसने मुद्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अधिकृत कर दिया है, मैदान को चारों ओर से घेरनेवाली जगह को पचास लाख रुपए प्रति १०० फुट की दर से बेचा गया है। इस १०० फुट के स्थान में २०-२० फुट के पांच पैनल लगेंगे। कुछ ४० फुट विज्ञापन बोर्डों की जगह २१-२५ लाख रुपए तक में बिकी है।

मगर श्री बिन्द्रा कहते हैं, "यह तो कुछ भी नहीं है। असल खर्च तो रिलायंस विश्व कप के उद्घाटन और समापन समारोह में होगा।" उनका कहना है, "निश्चित रूप से समारोह फिजूलखर्ची के अलावा कुछ भी नहीं, मगर खेल की भव्यता और महत्व को बरकरार रखने की दृष्टि से यह अच्छा भी होगा।" आई०पी० जे०एम०सी० ने बंगाल क्रिकेट एसोशियेसन को इसके लिए १५ लाख रुपए दिये हैं, मगर इसे सफलतापूर्वक संचालित कर पाना निश्चय ही एक बड़ी चुनौती का काम होगा।

—पंपा शास्त्री

साक्षात्कार/एन०के०पी० साल्वे

हम दो विश्व कप एक साथ कर सकते हैं

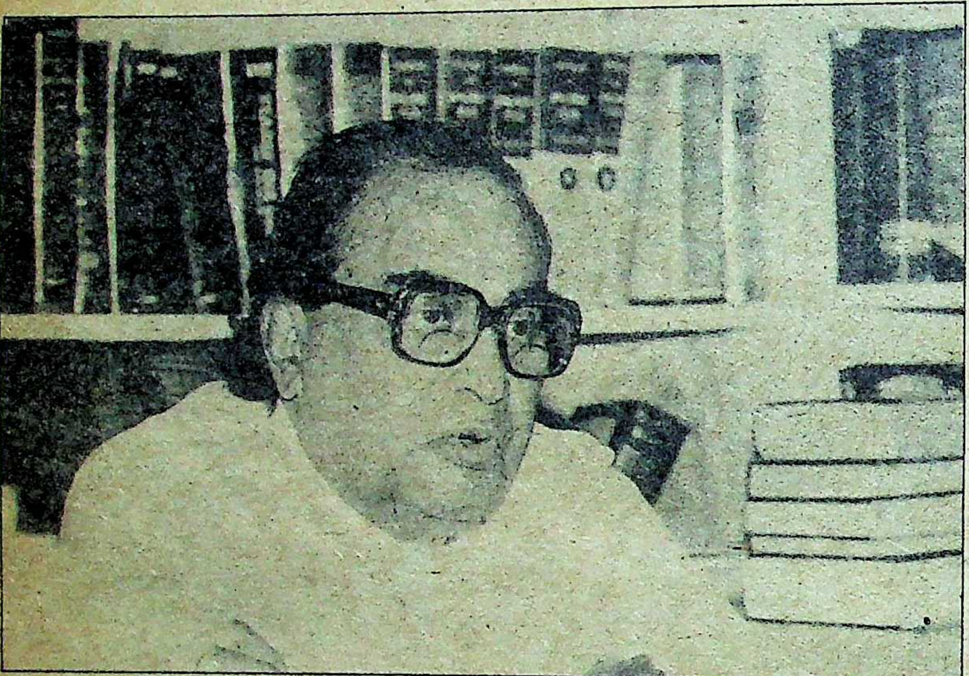

माया: रिलायंस विश्व कप जैसे बड़े आयोजन की तैयारियों और अनुभवों का जायजा आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपने कभी हताशा का अनुभव किया? आपकी सफलता में प्रमुख सहायता किसने की?

साल्वे: जब हमने फैसला करके इसके लिए प्रयास शुरू किया, तो समूचे आयोजन की विशालता का हममें से किसी को अंदाज नहीं था। जिन वित्तीय समस्याओं, सांगठनिक कार्यों और दूसरी कठिनाइयों का बाद में सामना करना पड़ा, वे हमारे लिए पूर्णतया नयी थीं। एक तरह से मुझे खुशी है कि इन कठिनाइयों का पता हमें पहले से नहीं था। यदि हम जानते कि इतना बड़ा बोझ हमारे सिर पर होगा और भारी चुनौतियों-समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो शायद फैसला करने के पहले हम सैकड़ों बार सोचते। जिस खुले दिल से भारत और पाकिस्तान के लोगों ने सहयोग किया, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने जो उदार सहायता की, वह अभूतपूर्व है। राष्ट्रपति जिया-उल-हक और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उदार दृष्टिकोण तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय के अपने मित्रों के हार्दिक सहयोग से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। हमने वस्तुतः हर क्षेत्र में तालमेल बिठाया है। हमारे साथ (भारत-पाक के) एक पूर्ण कार्यालय कार्य कर रहा है और प्रबंध एवं देखरेख का कार्यभार भारत और पाकिस्तान दोनों के हाथ में है, जिससे मैचों को सफलता मिले।

माया: आपके पिछले चंद महीने तो बड़ी भाग-दौड़ के रहे होंगे। आपने कितना समय यात्रा में बिताया?

साल्वे: मुझे ब्रिटेन की ४ या ५, आस्ट्रेलिया की २ और श्रीलंका और पाकिस्तान की एक-एक बार यात्रा करनी पड़ी। मुझे न्यूजीलैंड भी जाना था, पर भारी व्यस्तता के कारण संभव न हो सका। और फिर विभिन्न प्रबंधों के लिए मुझे देश के विभिन्न भागों की भी बहुत यात्रा करनी पड़ी।

माया: भारत और पाकिस्तान को टूर्नामेंट के बाद लगभग कितना धन मिलने वाला है?

साल्वे: हमारी आर्थिक जिम्मेदारियां इस टूर्नामेंट में इतनी बड़ी है कि हमारा खर्च ब्रिटेन में १९८३ में हुए व्यय से लगभग दोगुना होगा। हमें इसके लिए १८ लाख पाउंड की मंजूरी मिली है, जो पूर्णतया हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए है। फिर भारत और पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले अन्य खर्चे हैं। भारतीय और पाकिस्तानी बोर्डों को प्रत्येक को ४० से ५० लाख रु० के बीच मिलेगा। तमाम मैच केन्द्रों से हमें अच्छी रकम मिलेगी, ऐसी आशा है।

माया: कलकत्ता मैदान, जहां फाइनल मैच होगा, राज्य सरकार का है। क्या मैदान की तैयारी में कोई समस्या खड़ी हुई थी?

साल्वे: कलकत्ता मैदान से क्रिकेट बोर्ड की प्रबंधक समिति या भारत-पाक संयुक्त प्रबंधक समिति को कुछ लेना-देना नहीं है। यह समस्या सरकार से हल करने का भार बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) पर है। सीएबी ने मैदान की मरम्मत, सुधार और रखरखाव का व्यापक कार्य शुरू किया है।

माया: दिल्ली के बारे में आपका क्या कहना है? यहां की तैयारियों को लेकर कोई खास चर्चा नहीं सुनायी पड़ रही है। दिल्ली में मैच होगा भी इस बारे में दरअसल परस्परविरोधी खबरें मिल रही हैं।

साल्वे: दिल्ली में मैच जरूर होगा। दरअसल हुआ यह कि आस्ट्रेलिया से भारत आये पर्यवेक्षकों ने कहा था कि दिल्ली के स्टेडियम में सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। उन्होंने दिल्ली के मैदान में अनेक परिवर्तन और सुधार की मांग की थी। बदकिस्मती से दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने उन परिवर्तनों को करने व समुचित सुविधाएं जुटाने में थोड़ी ढील की। किंतु अब मैं समझता हूं कि सब कुछ लगभग ठीक-ठाक कर लिया गया है। किंतु अच्छा होता कि यह सब पहले हो जाता।

माया: बोर्ड आफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया (बीसीसीआई) और इंडो-पाक ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी (आईपीजेएमसी) धन की भागीदारी लाभ-हानि के आधार पर कैसे करने जा रही है?

साल्वे: भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर ८० लाख से एक करोड़ के बीच लाभ कमायेंगे, जो गारंटी राशि के रूप में होगी और जिसके हम हकदार होंगे। यह धन बोर्ड को दिया जायेगा। हमें अपने राज्यों के एसोसिएशनों से भी कुछ गारंटी राशियां प्राप्त होने जा रही हैं। इस गारंटी राशि और २ करोड़ २० लाख रु० की प्रायोजक राशि से हम अपना सारा खर्च उठाने जा रहे हैं। अब विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हमें ३ करोड़ ४२ लाख रु० की आवश्यकता है, देखिये क्या होता है।

माया: क्या इस प्रकार के अनुभव से भारत स्वतंत्र रूप से विश्व कप आयोजित करने में समर्थ होगा?

साल्वे: भारत निस्संदेह स्वतंत्र रूप से विश्व कप आयोजित कर सकता है। भारत में असीम साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि देश में क्रिकेट-प्रेमियों की बहुत बड़ी संख्या है। हमारे पास आवश्यक वित्तीय संसाधनों की भी कमी नहीं होगी। हम एक साथ दो विश्व कप आयोजित कर सकते हैं। और दोनों पूर्णतया सफल होंगे।

माया: क्या आप समस्त प्रबंधों से संतुष्ट हैं?

साल्वे: अब तो एसोसिएशनों को अपनी भूमिका निभानी है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। जब आपको पता चलता है कि सारे प्रबंध ठीक-ठाक हैं, तभी आप सफलता की आशा करते हैं। इसलिए मुझे कोई आशंका नहीं, बल्कि आशा है कि हमारे प्रबंध टूर्नामेंट को कामयाब बनायेंगे।

माया: क्या दक्षिण अफ्रीका की समस्या हल कर ली गयी है और क्या सभी पक्ष उससे संतुष्ट हैं?

साल्वे: हमारे सामने प्रमुख समस्या थी कुछ खिलाड़ियों के खेल के अनुबंध को लेकर। खासकर इंग्लैंड की टीम, जिसका दक्षिण अफ्रीका के साथ अनुबंध था। एक समय ऐसा आया था, जब इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था। 'इंटरनेशनल क्रिकेट कांफ्रेंस' की जून १९८७ की बैठक में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज ने प्रस्ताव पेश किया था कि जो देश दक्षिण अफ्रीका से अनुबंध करेगा, उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बहिष्कृत कर दिया जायेगा। उस समय लिया गया निर्णय प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। सौभाग्य से अगस्त में प्रवर समिति की बैठक में इस पर विचार हुआ। वह ऐसे समाधान की तलाश में है, जिससे इस मसले से कारगर ढंग से निपटा जा सके। मुझे आशा है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रवर समिति विचार-विमर्श कर रही है और इसकी अगली बैठक नवंबर में कलकत्ते में ठीक फाइनल के पूर्व होगी।

—पपा शास्त्री

साक्षात्कार/अनिल अंबानी

रिलायंस कप हमारा अंतिम पड़ाव नहीं

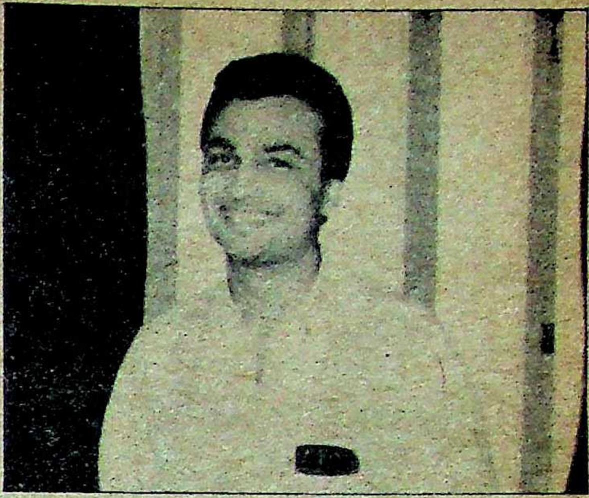

भारत में अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट स्पर्धा का परदा उठने ही वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० के युवा कार्यकारी निदेशक और रिलायंस कप—८७ के प्रायोजक अनिल अंबानी इस आयोजन से होने वाले प्रचार के साथ-साथ उपलब्ध लाभों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

"जबरदस्त प्रचार, हां। आप कल्पना कर सकते हैं, लगातार एक महीने तक 'रिलायंस' नाम उन लाखों लोगों के दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, जो भारत-पाकिस्तान के विभिन्न स्टेडियम तथा टेलीविजन पर इन मैचों को देखेंगे। रिलायंस कप—८७ से मिलने वाला प्रचार अकूत है। बहरहाल प्रचार इसका मात्र एक पहलू है, संपूर्ण नहीं।

"घटना को यदि इस दृष्टि से देखें कि राजनैतिक मतभेदों से विभाजित होकर भारत और पाकिस्तान दो देश बने, किंतु दोनों साथ मिल बैठे और इस बड़े आयोजन के लिए मित्र-भाव से काम किया। क्या यही महत्वपूर्ण अवसर का जनक नहीं है?

"जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक जयपुर में भारत-पाक टैस्ट मैच देखने आये, तो उन्होंने 'शांति के लिए क्रिकेट' की बात कही। हमें संकेत मिल गया और हमने इसे आदर्श वाक्य बनाया रिलायंस कप—८७ का।"

इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समारोह का विचार अनिल को ब्रिटेन में हुए विश्व कप मैच के दौरान आया। उन्होंने उसका अनुसरण किया और भारत-पाक संयुक्त प्रबंध समिति के सहयोग से विवरण तैयार किया। अब व्यापक रूप-रेखा के पश्चात इस महती योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने की स्थिति बनी है।

"अनेक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को भारतीय टेलीविजन दर्शकों तक प्रेषित करने वाला प्रायोजक आर०आई०एल० (रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०) अब पहली बार खेल कूद के संसार में पदार्पण कर रहा है और रिलायंस कप इसका अंतिम पड़ाव नहीं होगा।"

अनिल ने बताया— "हम खेलकूद के क्षेत्र में कुछ अति महत्वपूर्ण योजनाएं बना रहे हैं। इस परियोजना का नाम होगा 'रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन।' आप कह सकते हैं कि प्रायोजन के व्यवसाय से हम खेलकूद में कुछ बुनियादी कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। इसे हम वक्त की जरूरत मानते हैं। फाउंडेशन खिलाड़ियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, जिससे वे वंचित हैं। हम उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, साज-सामान, मैदान और अंतरराष्ट्रीय स्तर के 'ट्रेक्स' देंगे। हम अपने खिलाड़ियों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करायेंगे। विचार यह है कि प्रतिष्ठित और नये खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खेलकूद समारोहों के लिए तैयार किया जाये, जिससे खाली हाथ लौटने की परंपरा टूटे।

"रिलायंस स्पोर्टस फाउंडेशन की स्थापना अगले वर्ष की जायेगी, किंतु रिलायंस कप—८७ का तात्कालिक परिणाम है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीधा टेलीफोन संपर्क।

"हमने अधिकारियों से कहा कि हम उस देश से संपर्क करने में ४८ घंटे की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जिनके साथ हम ऐसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय खेलकूद समारोह में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम दोनों देशों में सीधी टेलीफोन सुविधा प्राप्त करने में सफल हुए। आशा है सरकार रिलायंस कप की समाप्ति के पश्चात यह प्रबंध भंग नहीं करेगी। देखिये आगे क्या होता है?"

—किरन मेहता

साक्षात्कार/बापू नाडकर्णी

हम कल मैच आयोजित कर सकते हैं

द बांबे क्रिकेट एसोसिएशन (बी०सी०ए०) दो रिलायंस कप मैचों का प्रबंध करने को तैयार है। पहला मैच १७ अक्तूबर को और दूसरा मैच ५ नवबर को खेला जायेगा। ५ नवबंर वाला मैच सेमीफाइनल होगा।

"हम इस आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बी०सी०ए० के अवैतनिक सचिव और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी बापू नाडकर्णी ने हंसते हुए आगे कहा, "आप चाहें तो कल मैच खेल सकते हैं।"

४० हजार की दर्शक क्षमता वाले वानखेडे स्टेडियम के ठसाठस भरने की आशा है। बी०सी०ए० आयोजकों के लिए यह कोई नयी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले भी ऐसी आयोजनों को बखूबी संभाल चुके हैं। इस स्टेडियम के लिए जो सर्वथा नयी बात होगी, वह है व्यापक 'मीडिया' का आगमन, जो इस महानगरी में होने वाले रिलायंस कप, '८७ मैचों के साथ रहेगा।

छह टेलीविजन कैमरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों को विभिन्न कोणों से फिल्मायेंगे। विभिन्न नेटवर्कों के टी०वी० उद्घोषकों के लिए चार बूथ होंगे और रेडियो प्रसारणों के लिए भी समान संख्या में बूथ होंगे। स्थानीय प्रेस और अन्य 'मीडिया' के लिए अतिरिक्त स्थान सुरक्षित होंगे। संभावित ६० सदस्यीय विश्व प्रेस दल को स्थान प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रेस गैलरी का विस्तार किया जा रहा है।

बापू नाडकर्णी इस बड़ी योजना में तन-मन से लगे हैं। उनकी जिम्मेवारी पहली गेंद से अंतिम गेंद तक संपूर्ण देखरेख, व्यवस्था और रख-रखाव से अभिन्न रूप से जुड़ी है। वह कहते हैं, "यदि मैदान के अंदर या बाहर कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो उसकी जवाबदेही मेरी होगी।"

बापू एक अधिकारी के रूप में बी०सी०ए० के सचिव मात्र नहीं, बल्कि रिलायंस कप,—८७ के भारतीय एकादश की निर्वाचन समिति के [illegible]

—[illegible] मेहता

खेल की शर्तें

होने वाले रिलायंस कप में अधिक-से-अधिक खेल संभव हो, इसके लिए आयोजकों ने कुछ विशेष 'खेल की शर्तें' बनायी हैं। ये शर्तें क्रिकेट के सर्वमान्य नियमों के साथ-साथ लागू होंगी। मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :—

१-प्रत्येक टीम अपने १४ खिलाड़ियों के नाम भारत-पाकिस्तान बोर्ड को २९ सितंबर से पहले भेजेगी। केवल प्रबंध समिति द्वारा विशेष छूट के बाद ही इन नामों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है।

२-खेल की अवधि और विश्राम : साधारणतया—

प्रथम पारी ९.०० से १२.३५ तक
विश्राम १२.३५ से १३.१५ तक
दूसरी पारी १३.१५ से १६.५० तक

(क) अगर पहली पारी १२.३५ से पहले ही समाप्त हो जाये, तो विश्राम उसी समय से आरंभ होगा और ४० मिनट बाद दूसरी पारी शुरू होगी।

(ख) अगर १६.५० तक दूसरी पारी के निर्धारित ओवर न पूरे हों, तो खेल तब तक चलेगा, जब तक परिणाम नहीं प्राप्त होते या निर्धारित ओवर समाप्त नहीं होते।

(ग) देर से आरंभ या किसी कारण रुक गये खेल में विश्राम की अवधि कम की जा सकती है।

अगर ६० मिनट का समय नष्ट हुआ है, तो विश्राम ३० मिनट का होगा और अगर १२० से अधिक मिनट का समय नष्ट हुआ है तो विश्राम १० मिनट का होगा।

(घ) हर पारी में दो बार 'ड्रिंक्स' की व्यवस्था होगी। इसकी अवधि ५ मिनट से अधिक नहीं होगी।

३-प्रत्येक टीम ५० ओवर की एक पारी खेलेगी। एक ओवर ६ गेंदों का होगा।

(क) प्रारंभिक 'पूल' मैचों में दो दिन भी लग सकते हैं। दूसरे दिन तभी खेल होगा जबकि पहले दिन कोई खेल न हुआ हो।

(ख) सेमीफाइनलों में दो दिन और फाइनल में तीन दिन भी लग सकते हैं। अगर कोई टीम या टीमें अपने न्यूनतम २५ ओवर की बल्लेबाजी पहले दिन पूरा नहीं कर पातीं, तो खेल सेमीफाइनल में दूसरे दिन होगा और फाइनल में तीसरे दिन भी हो सकता है।

दूसरे और तीसरे दिन का खेल उसी बिन्दु से आरंभ होगा जहां खेल पहले या दूसरे दिन समाप्त हुआ था।

४-(क) अगर १२.३५ क्षेत्र रक्षण कर रही टीम निर्धारित ५० ओवर गेंदबाजी न कर सकी, तो बल्लेबाजी कर रही टीम की पारी उस ओवर के बाद समाप्त हो जायेगी और क्षेत्ररक्षक टीम को भी उतने ही ओवर की बल्लेबाजी मिलेगी, जितने ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है।

(ख) अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, ५० ओवर से पहले ही, सारे विकेट खो देती है, तो दूसरी टीम को ५० ओवर की बल्लेबाजी करने की छूट होगी।

५-जहां खेल देर से आरंभ हो या किसी कारणवश रुका हो :

(क) वहां शेष समय में, गेंदबाजी करने वाले ओवर की संख्या, चार मिनट प्रति ओवर के हिसाब से निर्धारित की जायेगी।

(ख) वहां निर्धारित खेल समय निश्चित करने के बाद, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बल्लेबाजी करने की अवधि सूचित की जायेगी और चार मिनट प्रति ओवर के हिसाब से दूसरी टीम गेंदबाजी करेगी। अगर दूसरी टीम निर्धारित समय में अपने पूरे ओवर फेंक नहीं पाती, तों उन्हें 'दण्ड नियम' के अनुसार जुर्माना देना होगा।

(ग) वहीं अगर दूसरी टीम की बल्लेबाजी के समय खेल रुका और उस टीम को उतने ओवर बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिलता जितना पहली टीम को मिला है, तो बचे समय में चार मिनट प्रति ओवर के हिसाब से फिर ओवर निर्धारित किये जायेंगे।

(घ) वहां केवल जब पहली टीम अपने निर्धारित ओवर से पहले ही आउट हो जाती है तब ही दूसरी टीम पहली टीम से अधिक ओवर की बल्लेबाजी कर सकती है।

६-(क) पचास ओवर के मैच में कोई भी गेंदबाज दस ओवर से अधिक गेंदबाजी नहीं करेगा।

(ख) लेकिन अगर ओवर कम हो जायें, तो वहां ओवर की सख्या प्रति गेंदबाज फिर से निर्धारित होगी। उदाहरण के लिए ३३ ओवर की गेंदबाजी में तीन गेंदबाज सात-सात ओवर गेंदबाजी करेंगे ओर दो गेंदबाज छह-छह ओवर करेंगे।

(ग) अगर कोई गेंदबाज अपना ओवर पूरा नहीं कर पाता, तो दूसरा गेंदबाज उसके जारी ओवर को पूरा करेगा। परंतु गेंदबाजी विश्लेषण में गेंदबाज के नाम के सामने पूरा ओवर दिखाया जायेगा।

७-(क) केवल विपक्षी कप्तान की अनुमति और अंपायरों की सहमति के बाद ही कोई अतिरिक्त खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण कर सकता है।

(ख) अगर कोई खिलाड़ी अपने कपड़े या बूट बदलना चाहता है, तो उसे मैदान के बाहर जाना होगा और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी उसकी जगह क्षेत्ररक्षण नहीं करेगा।

(ग) अगर किसी क्षेत्ररक्षक को बाहरी चोट लगती है और उसे मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो चिकित्सा के बाद मैदान पर वापस आकर वह फौरन ही गेंदबाजी कर सकता है। अंदरूनी चोट (जैसे मांस पेशी में तनाव या खिंचाव) में यह नियम लागू नहीं होगा।

८-(क) पिच, खेल का मैदान, मौसम और रोशनी कहां तक खेल के लिए उपयुक्त हैं, इस बात का निर्णय केवल अंपायर ही करेंगे।

(ख) खराब रोशनी के कारण खेल रोकने या समाप्त करने से पहले अंपायर बल्लेबाजी कर रही टीम के कप्तान से पूछेंगे कि वे इस रोशनी में खेलना चाहते हैं या नहीं? अगर कप्तान "हां" कहता है, तो खेल जारी रहेगा। परंतु अगर थोड़ी देर बाद कप्तान खेल रोकने या समाप्त करने के लिए कहता है, तो अंपायर पहलें इस बात का निर्णय करेंगे कि रोशनी और भी कम हो चुकी है और बल्लेबाजी में जोखम है तथा चोट लग जाने का डर है। इसके बाद ही खेल रोका जा सकता है।

(ग) विकेट और पिच पर आ रही स्टेडियम की परछाइयों के विरुद्ध कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी। 'अधिक-से-अधिक खेल' का सिद्धांत हर समय ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) खेल के दौरान अंपायर हर प्रकार के उन उपकरणों की सहायता ले सकता है, जिनके द्वारा जमीन या 'पिच' सुखायी जा सकती है। इस कार्य के लिए अंपायरों द्वारा कप्तानों को सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं।

९-इन खेलों में बल्लेबाजी कर रही टीम का कप्तान कभी भी अपनी पारी घोषित नहीं कर सकता।

१०-किसी भी तरह से समय नष्ट करना ठीक नहीं है। अंपायर हर समय इस बात का ध्यान रखेंगे।

(क) प्रारंभिक पूल मैचों में—निर्धारित ओवर से अगर एक ओवर कम गेंदबाजी की गयी है, तो गेंदबाजी कर रही टीम पर १००० पाउंड का जुर्माना होगा, अगर दो ओवर तो पहले ओवर का १००० पाउंड और दूसरे का १४०० पाउंड। पहले ओवर के बाद, हर ओवर पर, १४०० पाउंड का जुर्माना देना पड़ेगा।

(ख) सेमीफाइनल में—पहले ओवर का २००० पाउंड और बाकी ओवर पर २८०० पाउंड।

(गं) फाइनल में—पहले ओवर पर ३००० पाउंड और अन्य पर ४२०० पाउंड का जुर्माना होगा।

(घ) अगर बल्लेबाजी कर रही टीम 'समय नष्ट' करने के लिए दोषी पायी गयी और अगर यह तय हुआ कि उसने दूसरी टीम को निर्धारित ओवर फेंकने में बाधा डाली है, तो उन पर भी उसी तरह से जुर्माना लगेगा जैसे 'गेंदबाज टीम' पर लगाये जा सकते हैं।

(च) जुर्माने की धनराशि प्रारंभिक, सेमीफाइनल या फाइनल मैचों में प्राप्त धनराशि से काट ली जायेगी। अगर जुर्माने की धनराशि संपूर्ण पुरस्कार धनराशि से अधिक है, तो उस टीम को मिलने वाली 'गारंटी मनी' से शेष धनराशि काट ली जायेगी।

(छ) 'मैन आफ द मैच' की धनराशि टीम की धनराशि से अलग होगी और यह दोनों एक साथ नहीं मिलाये जायेंगे

११-परिणाम—

I- 'टाई' की स्थिति में—(क) जिस टीम के कम विकेट गिरे होंगे, उसकी विजय होगी।

(ख) अगर दोनों ही टीमें आउट हो जाती हैं, तो जिसकी 'रन बनाने की गति' अधिक होगी वह टीम जीतेगी।

(ग) अगर (क) और (ख) से निर्णय नहीं होता तो, देखा जायेगा कि किसका स्कोर अधिक है :—

पहले चालीस ओवर बाद
फिर तीस ओवर बाद
फिर पच्चीस ओवर बाद
फिर बीस ओवर बाद

और अंत में पन्द्रह ओवर बाद

(घ) अगर निर्णय इसके बाद भी नहीं होता तो मैच 'टाई' माना जायेगा।

II- (क) अगर कोई मैच असमाप्त रहता है, तो वह टीम विजयी घोषित होगी जिसने संपूर्ण पारी में अधिक गति से प्रति ओवर में रन बनाये हैं। परंतु कम-से-कम २५ ओवर की गेंदबाजी अनिवार्य है।

(ख) अगर कोई टीम निर्धारित ओवर से पहले ही आउट हो जाती है, तो रन बनाने की गति निर्धारित ओवर के आधार पर ही निकाली जायेगी। अगर तब भी यह गति बराबर हो, तो पहले २५ ओवर में जिस टीम की रन बनाने की गति अधिक होगी, वही टीम विजेता मानी जायेगी।

(ग) अगर खेल बीच में रुकता है और दूसरी टीम को कम ओवर बल्लेबाजी करने का अवसर मिलता है, तो कम-से-कम पच्चीस ओवर की बल्लेबाजी अनिवार्य होगी। मान लिया पहली टीम ने ५० ओवर में २५० रन बनाये और दूसरी टीम को केवल २८ ओवर की बल्लेबाजी मिली। तो दूसरी टीम को १४० से अधिक रन बनाने होंगे अर्थात पहली टीम की रन बनाने की गति से अधिक रन गति रखनी पड़ेगी। इससे 'टाई' या 'कोई परिणाम नहीं' की संभावना समाप्त हो जायेगी।

(घ) अगर दूसरी टीम को पच्चीस ओवर की बल्लेबाजी नहीं मिली, तो मैच में कोई परिणाम नहीं होगा।

१२-फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण—

(I) प्रत्येक ग्रुप में टीमों के स्थानों का निर्धारण, उनके द्वारा प्रारंभिक चक्र के मैचों में अर्जित अंकों के आधार पर किया जायेगा।

अंक निर्धारित करने का क्रम इस प्रकार होगा :—

प्रत्येक विजेता टीम को ४ अंक
'टाई' मैच के लिए २ अंक
'परिणाम रहित' मैच के लिए २ अंक
हारने वाली टीम को ० अंक

(II) टीमों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने की स्थिति में ग्रुप में स्थान का निर्धारण (क) पहले अधिक विजय अर्जित करने के आधार पर किया जायेगा (ख) और अगर उसके बाद भी स्थान निर्धारित नहीं हो पाता, तो प्रारंभिक मैचों के औसत 'रन-रेट' को आधार माना जायेगा।

(III) सेमीफाइतल में ग्रुप 'ए' की प्रथम टीम ग्रुप 'बी' की दूसरी टीम और ग्रुप (ए) की दूसरी टीम, ग्रुप (बी) की प्रथम टीम से खेलेगी।

(IV) अगर सेमीफाइनल मैच 'परिणाम रहित' या 'टाई' घोषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपने ग्रुप के प्रारंभिक मैचों में प्रथम स्थान वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी।

(IV) अगर किन्हीं कारणों से फाइनल मैच 'परिणाम-रहित' या 'टाई' घोषित होता है, तो दोनों टीमें संयुक्त विजेता होंगी।

१३-निर्णायक—

प्रत्येक मैच में एक निर्णायक नियुक्त किया जायेगा, जो मैच आरंभ होने के एक दिन पहले अंपायरों और कप्तानों से बातचीत करके खेल नियमों की समरूप व्याख्या निर्धारित करेगा और कोई विवाद होने पर निर्णायक की भूमिका निभायेगा। किन्हीं कारणों से कम ओवर फेंकने की स्थिति आने पर या बाद में खेलने वाली टीम को कम रन बनाने का निर्धारण करने में अंपायरों की सहायता करेगा।

—मनीष देव

समूह 'अ' की टीमें

भारत में खेले जाने वाले १७ रिलायंस कप मैचों का विवरण (समूह 'ब' के तीन मैचों सहित)

मैच दिनांक	रिजर्व दिनांक	मैच	स्थान
९-१०-८७	१०-१०-८७	भारत बनाम आस्ट्रेलिया	मद्रास
१०-१०-८७	११-१०-८७	न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे	हैदराबाद
१३-१०-८७	१४-१०-८७	आस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे	मद्रास
१४-१०-८७	१५-१०-८७	भारत बनाम न्यूजीलैंड	बंग्लौर
१७-१०-८७	१८-१०-८७	भारत बनाम जिम्बाब्वे	बंबई
१८-१०-८७	१९-१०-८७	आस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड	इंदौर
२१-१०-८७	२२-१०-८७	वेस्ट इंडीज बनाम श्रीलंका	कानपुर पूल 'बी'
२२-१०-८७	२३-१०-८७	भारत बनाम आस्ट्रेलिया	नयी दिल्ली
२३-१०-८७	२४-१०-८७	न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे	कलकत्ता
२६-१०-८७	२७-१०-८७	भारत बनाम जिम्बाब्वे	अहमदाबाद
२६-१०-८७	२७-१०-८७	इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज	जयपुर 'बी६'
२७-१०-८७	२८-१०-८७	आस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड	चंडीगढ़
३०-१०-८७	३१-१०-८७	आस्ट्रेलिया बनाम जिम्बांब्वे	कटक
३०-१०-८७	३१-१०-८७	इंग्लैंड बनाम श्रीलंका	पूणें पूल 'बी'
३१-१०-८७	१-११-८७	भारत बनाम न्यूजीलैंड	नागपुर
५-११-८७	६-११-८७	सेमीफाइनल	बंबई
८-११-८७	९-११-८७ १०-११-८७	फाइनल	कलकत्ता

समूह 'ब' की टीमें

पाकिस्तान में खेले जाने वाले १० मैचों का विवरण

मैच दिनांक	रिजर्व दिनांक	मैच	स्थान
८-१०-८७	९-१०-८७	पाकिस्तान बनाम श्रीलंका	हैदराबाद
९-१०-८७	१०-१०-८७	वेस्टइंडीज बनाम इग्लैंड	गुजरानवाला
१२-१०-८७	१३-१०-८७	पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड	रावलपिंडी
१३-१०-८७	१४-१०-८७	श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज	करांची
१६-१०-८७	१७-१०-८७	पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज	लाहौर
१७-१०-८७	१८-१०-८७	इंग्लैंड बनाम श्रीलंका	पेशावर
२०-१०-८७	२१-१०-८७	पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड	कराची
२५-१०-८७	२६-१०-८७	पाकिस्तान बनाम श्रीलंका	फैसलाबाद
३०-१०-८७	३१-१०-८७	पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज	कराची
४-११-८७	५-११-८७	सेमीफाइनल	लाहौर

मैच का समय

पहली पारी	*९.०० सुबह से -*	*१२.३५ दोपहर तक*
लंच	*१२.३५ से -*	*१३.१५ तक*
द्वितीय पारी	*१३.१५ दोपहर से-*	*१६.५० शाम तक*

आभास कोमलता का,
अहसास उमंग भरा...

बनियान, जांघिये, ब्रा तथा अन्य उत्पादन

आपके परिवार के लिये
आपके परिवार के लिये
डोरा एक विश्वसनीय नाम....
अपनी उत्कृष्टता के लिये पूरे भारत वर्ष में करोड़ों लोगों का
अभिन्न अंग बन चुका है, डोरा का सुखद स्पर्श तथा तन-मन को छू जाने
वाली इसकी फूल जैसी कोमलता, आपके जीवन में नई उमंगों का अहसास देती है।

HP INDIA
एच. पी. टेक्सटाइल मिल्स
कलकत्ता - अहमदाबाद - नई दिल्ली

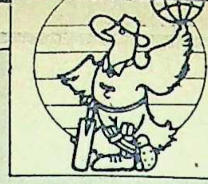

'पावर' का खेल

नयी दिल्ली के पाच सितारा होटल में कमरा नं० २१० क्रिकेट की फाइव स्टार सामग्रियों से भरा पडा है। बल्लों से भरे बाक्स, पैड, जूते और वे तमाम चीजें जो एक टेस्ट खिलाड़ी इस्तेमाल करता है। इन सभी सामग्रियों पर 'पावर' का निशान अलग दिखता है। दर्शन लाल को पावर कंपनी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां रखा है, जिससे रिलायंस कप में भाग ले रहे खिलाड़ियों को कोई भी चीज तुरंत उपलब्ध की जा सके।

इसी दौरान मनोज प्रभाकर आते हैं और दर्शन लाल से शिकायती लहजे में कहते हैं, "भाई ये जूता मुझे फ़िट नहीं बैठ रहा।" दर्शन लाल जाकर दूसरा जोड़ा लाते हैं और प्रभाकर से पहनकर देखने को कहते हैं। "हां यह ठीक है"-प्रभाकर मुस्कराते हुए धन्यवाद देकर चले जाते हैं। यह दृश्य दिन में बीसियों बार सामने आता है और दर्शन लाल हर तरह से खिलाडियों को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं।

सुनील गावस्कर को छोड़कर लगभग सभी खिलाड़ी पावर का सामान उपयोग में लाते हैं। गावस्कर 'सेंसपरेल ग्रीनलैंड' द्वारा निर्मित सामान उपयोग करते हैं। 'सनी टनी' नाम का बल्ला आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खासियत है, बल्कि इसलिए कि यह सनी के बल्ले जैसा बनाया गया है। 'पावर' द्वारा बनाया गया सामान खिलाड़ियों की व्यक्तिगत पसंद को ध्यान में रखकर तैयार होता है। मसलन, कपिलदेव के लिए सबसे भारी बल्ला, क्योंकि वे ताकत पर भरोसा करते हैं। अजहरुद्दीन और दिलीप वेंगसरकर जैसे कलात्मक बल्लेबाजों के लिए हल्के बल्ले। इसी तरह रवि शास्त्री की छह फुट तीन इंच की लंबाई को ध्यान में रखकर लंबे हैंडल वाला बल्ला 'पावर' ने बनाया है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि 'पावर कंपनी' खिलाड़ियों पर बेहिसाब धन खर्च कर रही है, लेकिन इससे बेशकीमती प्रचार भी तो हासिल होगा। लाखों दर्शक खिलाड़ियों के बैट, पैड आदि पर महीने भर 'पावर' का नाम देखेंगे। इससे पूरे देश में स्थित 'पावर' के शो रूमों में बिक्री कई गुना बढ़ जायेगी। 'पावर' का सिद्धांत 'खिलाड़ियों की सेवा' निश्चित रूप से अच्छा है, मगर रिलायंस कप के जरिये वे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं।

सभी खिलाड़ी दर्शन लाल को इज्जत और प्यार देते हैं। आमतौर पर चार-पांच खिलाड़ी तो उन्हीं के कमरे में आराम करते मिलते हैं। १९८४ के बाद इस मुहिम के तहत वे देश भर में घूम चुके हैं। उनकी यात्रा और रहने-खाने का पूरा खर्च कंपनी देती है। वे कहते हैं "सभी खिलाड़ियों से मेरे मधुर संबंध हैं, उनसे भी जो मेरी कंपनी का सामान उपयोग नहीं करते। सुनील 'पावर' का सामान उपयोग नहीं करते, मगर हम दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं।"

यह पूछने पर कि क्या पावर अन्य देशों के खिलाड़ियों को भी क्रिकेट की सामग्री देगा? दर्शन लाल ने जवाब दिया, "हां, हम हर जरूरतमंद क्रिकेट खिलाड़ी को सामान देंगे।" क्रिकेट के सभी सामान अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनने के बावजूद अभी तक भारत में अच्छी गेंद नहीं बन पा रही है। बीच में बाधा न पड़े इसलिए गेंद विदेशों से मंगायी जाती हैं। निश्चित रूप से गेंद जल्दी खराब होने के लिए भारतीय पिचें ज्यादा दोषी हैं। भारत में ज्यादातर मैदानों में घास नहीं है, इसलिए गेंद बल्ले से पिटनें की बजाय नंगे मैदान में रगड़ खाकर जल्दी खराब होती हैं। मगर विदेशी गेंदें यहां फिर भी देशी गेंदों से ज्यादा चलती हैं। दर्शन लाल 'सोनेक्स' नाम से क्रिकेट की गेंद बनाने की योजना बना रहे हैं, मगर अभी इसके लिये क्रिकेट हस्तियों की मंजूरी मिलनी बाकी है।

क्रिकेट की पोशाक भी खिलाड़ियों के हिसाब से बनायी गयी हैं। शर्ट 'लार्ज' और 'मीडियम' साइज की बनी हैं जो कपिल से लेकर गावस्कर तक को फिट बैठती हैं। मगर पतलूनों को नाप-जोख के बाद ही बनाया गया है, क्योंकि शास्त्री की लंबी टांगों और अजहर की पतली कमर का ध्यान में रखना जरूरी है।

—अनिल शर्मा

फर्क पांच दिवसीय और एक दिवसीय क्रिकेट का

वेंकट सुंदरम

क्रिकेट का खेल पिछली एक शताब्दी में दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलो-दिमाग में रच-बस गया है। काफी की दुकानों, बार और खाने की मेज पर अकसर यह गरमागरम बहस होती है कि कौन सा क्रिकेट बेहतर है—पांच दिन का टैस्ट क्रिकेट या सीमित ओवरों का एक दिवसीय क्रिकेट। मुझसे अकसर पूछा जाता है कि क्या किसी दिन एक दिवसीय क्रिकेट हमेशा के लिए पारंपरिक टैस्ट क्रिकेट की जगह ले लेगा। कद्रदानों की निगाह में टैस्ट क्रिकेट का कोई विकल्प नहीं हो सकता। टास के बाद टैस्ट मैच में जो उतार-चढ़ाव आते हैं, वैसा नजारा कोई और खेल पेश नहीं कर सकता।

बड़ी एहतियात से योजना और रणनीतियां बनाना, पिच की चाल-ढाल और बारिश, ओस व रोशनी के मुताबिक शारीरिक गतिविधियां बदलना, शारीरिक क्षमता का बेहतरीन परीक्षण, लंबे समय तक एकाग्रता बनाये रखना और चार पारियों में अपनी रणनीति लागू करना और प्रतिद्वंद्वियों की रणनीति को काटना-कुछ ऐसी खूबियां हैं जो किसी और खेल में हो ही नहीं सकतीं।

हर क्षण रोमांच : श्रीकांत को स्टम्पिंग करने की कोशिश में विकेट कीपर

कुछ साल पहले इंग्लैंड के क्रिकेट मैदानों में जब दर्शकों की भीड़ कम होने लगी, तो मजबूर होकर वहां के अधिकारियों ने एक ऐसे प्रकार के क्रिकेट के बारे में सोचा, जिसमें समय तो कम लगे, पर वह भारी भीड़ जुटा और बड़े प्रायोजकों को आकर्षित कर सके। ऐसा इसलिए जरूरी था, क्योंकि १९६० के दशक के आखिरी सालों में इंग्लैंड की कई काउंटियों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी थी। अतः नयी रणनीति के तहत सीमित ओवर के क्रिकेट की शुरुआत की गयी। १९७० के दशक के आखिरी सालों में क्रिकेट पर हुए कैरी पैकर के धावे ने सीमित ओवरों के क्रिकेट को नयी ताकत दी। कैरी पैकर ने दिन-रात के मैच शुरू कराये, सफेद की बजाय खिलाड़ियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाये और टेलीविजन पर ऐसे मैचों का व्यापक प्रसारण किया, जिससे सीमित ओवर के क्रिकेट मैचों में दर्शकों की संख्या नये रिकार्ड बनाने लगी। टैस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके हाथ सोने की खान लग गयी और उनकी खाली झोली तेजी से भरने लगी। दर्शक पांच दिन तक लंबी खिंचती लड़ाई देखते-देखते बोर हो गये थे। यह लड़ाई अकसर नीरस ड्रा में खतम होती थी। अचानक उन्हें ऐसा क्रिकेट मिला, जिसमें नतीजा निकलना पक्का था। कलात्मक बल्लेबाजी की अब जरूरत नहीं थी और न ही गेंदबाज को बहुत बारीकी और होशियारी से रणनीति बनाने की। अब रनों, विकेटों और हर पल रोमांच का महत्व हो गया।

मौजूदा तेज रफ्तार जमाने के मुताबिक क्रिकेट भी ढल गया है। हम लोग ऐसे युग में रह रहे हैं, जहां मेज पर बैठकर खाना खाने की जगह डिब्बा बंद भोजन आ गया है। आजकल ऐसी चीजों की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ऐसे माहौल में यह अजूबा ही लगता अगर महान खेल क्रिकेट अलग रंग-ढंग नहीं अपनाता। क्रिकेट ने साहित्य और राजनीति में जगह बनायी। 'क्रिकेट मत खेलो' यह मुहावरा व्यापक रूप से विभिन्न संसदों में इस्तेमाल हुआ, ऐसे खेल के लिए यह जरूरी था कि वह अपने समर्थकों की जरूरत के मुताबिक बदले, लिहाजा एक दिन के क्रिकेट ने खाली जगह को भर दिया।

शारीरिक दमखम, एकाग्रता और तकनीक जरूरी है पांच दिन के क्रिकेट के लिए, जबकि शानदार क्षेत्ररक्षण और नपी-तुली गेंदबाजी चाहिए एक दिन के क्रिकेट के लिए। एक दिन के क्रिकेट के साथ गड़बड़ यह है कि अकसर इसमें क्रिकेट की कलात्मकता देखने को नहीं मिलती। बल्लेबाज लगभग हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करने लगता है। कई मामलों में एक दिन का क्रिकेट पूरी तरह नकारात्मक क्रिकेट है। गेंदबाज है, तो उसकी कोशिश यही रहती है कि बल्लेबाज को रन न बनाने दिये जायें, उसे आउट करने की वह कोई जरूरत नहीं समझता।

पांच दिन का क्रिकेट या एक दिन का क्रिकेट—यह बहस तो निरंतर जारी रहेगी, पर मैं अपनी बात महान खेल पत्रकार रे राबिंसन की बात के साथ ही खतम करता हूं। राबिंसन ने मुश्ताक अली और विजय मर्चेंट की प्रारंभिक जोड़ी के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि दोनों के मिजाज एक दूसरे से ऐसे अलग थे, जैसे कि एक चावल तो दूसरा कढ़ी, लेकिन एक जोड़ी के रूप में दोनों एक जैसे असरदार। यह सही है कि एक दिन का क्रिकेट और टैस्ट क्रिकेट का अपना-अपना व्यक्तिगत चरित्र है, पर दोनों ही तरह का क्रिकेट देखने लायक है और दोनों ही क्रिकेट की दुनिया के लाखों लोगों को पर्याप्त मनोरंजन मुहैया कराते हैं। वेंकट सुंदरम

सबसे मजबूत दावा पाकिस्तान का है

इसमें कोई शक नहीं कि एक दिवसीय मैच बहुत लोकप्रिय हैं, मगर इनमें भाग लेने वाली टीमों के लिए ये बहुत मुश्किल भरे होते हैं। उनसे ढेरों अपेक्षाएं की जाती हैं, इस वजह से वे तनावग्रस्त भी रहती हैं। लेकिन इस तनाव पर विजय पाकर जो टीम जीत हासिल करे, वास्तव में वही महान टीम कहलाती है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उक्त बात कई बार सिद्ध की है। यदि पिछले रिकार्डों और प्रदर्शनों को मद्दे नजर रखा जाये, तो पाकिस्तान द्वारा रिलायंस कप जीतना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। इमरान खान की कप्तानी में पाक टीम को बेशुमार सफलताएं हासिल हुई हैं। हाल में उसने इंग्लैंड को उसी की जमीन पर हराया है। इस सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आखिरी क्षण तक जूझने की बेमिसाल क्षमता है।

रिलायंस कप पर निगाह : इमरान छाया : सुरेश सुर्वना

पिछले दो विश्वकपों (१९७९ और १९८३) में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों ही बार सेमीफाइनल तक पहुंचने में उसे सफलता मिली। भारत की तरह वह कभी न तो बिलकुल प्रभावहीन रहा और न ही उसे अप्रत्याशित जीत मिली। उसने कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं जीता है। देखा जाये, तो विश्व चैंपियनशिप क्रिकेट और राथमेंस कप में भारत के हाथों हारने के बाद ही पाक टीम का उभरना प्रारंभ हुआ।

विश्व की अन्य सभी टीमों की तरह पाकिस्तान के अच्छे प्रदर्शन का सारा दारोमदार दो-तीन खिलाड़ियों के कंधों पर हीं है। प्रतिद्वंद्वी टीमों के लिये इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, सलीम मलिक और अब्दुल कादिर ही असल सिरदर्द साबित होंगे। इंग्लैंड पर मिली विजय के बाद इमरान के हौसले बुलंद हैं। इस समय वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक हैं। लगातार मिल रही सफलता के कारण उसने अपना गुस्सैल और असहयोगी रवैया त्याग दिया है और इस समय टीम को एकजुट रखने में लगा है।

यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि पूर्व कप्तान मियांदाद की बनिस्बत इमरान को नये खिलाड़ियों का सहयोग ज्यादा मिलेगा। अपने खेल की वजह से भी वह टीम की अगुवाई करेगा। अपनी घातक आउट स्विंगर्स से वह गेंदबाजों का हौसला बढ़ायेगा। हाल में उसकी बल्लेबाजी में भी सुधार हुआ है, अतः मौके पर बल्लेबाजी की बागडोर सभालने की कूबत भी उसमें है।

पाकिस्तानी बल्लेबाजी मुख्य रूप से मियांदाद पर ही निर्भर करेगी। बल्ले से सर्वश्रेष्ठ और खेल भावना से घटिया मियांदाद यह काम बखूबी कर सकते हैं। वह 'क्रिकेट किंग' कम बार ही छोटे स्कोर पर आउट हुआ है। उसके खेल की परिभाषा में यही कहा जा सकता है कि वह 'नियंत्रित हमला' करता है। छोटे-छोटे सिंगल्स और तगड़े प्रहारों के जरिये विपक्षी टीम पर वह छा जाता है। गेंदबाज कुछ कर पायें इसके पहले ही वह उन पर हावी हो जाता है। उसका आत्मविश्वास इस सबमें उसकी सहायता करता है। गावस्कर के १०,००० रन के रिकार्ड तोड़ने की संभावनाएं यदि किसी खिलाड़ी में नजर आती हैं तो वह मियांदाद ही हैं। दर्शकों के लिए मियांदाद का खेल भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। प्रतिद्वंद्वी टीम अगर इस पर हावी हो सके तो उनका काम आसान हो जायेगा।

इमरान के साथ गेंदबाजी की शुरुआत के लिये वसीम अकरम की खोज पाकिस्तान के लिये वरदान सिद्ध हुई है। अकरम की खासियत केवल तेजी ही नहीं है, बल्कि वह घटिया पिच पर भी गेंद को उठाने की आश्चर्यजनक क्षमता रखता है। गेंद का कोण और उसका लाइन लेंथ से तालमेल एक दिवसीय मैच में बहुत जरूरी होता है, जो कि अकरम की गेंदों में भरपूर देखने को मिलता है। गुड लेंथ से सीने की ऊंचाई तक गेंद को उठाकर वह बल्लेबाज को परेशान कर देता है। कभी-कभी तो वह इमरान खान से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। दूसरी तरफ वह अपनी छह फुट ऊंचाई का लाभ उठाकर अंधाधुंध बल्लेबाजी करने में भी माहिर है। पिछली भारत-पाक शृंखला में अकरम के प्रदर्शन से भारतीय गेंदबाजों ने निश्चित रूप से सबक लिया होगा।

अब्दुल कादिर की लेग स्पिन भारतीय बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पायेगी, क्योंकि स्पिनर को खेलने का उनके पास खासा तजुर्बा है। लेकिन वेस्टइंडीज जैसी टीमों को, जिन्हें तेज गेंदबाजों को खेलने का अभ्यास है, कादिर एक कयामत सिद्ध हो सकते हैं। उनका बालिंग एक्शन भी बल्लेबाजों को भ्रम में रखता है। लगता यह है कि गेंद तैरती हुई आफ स्टंप पर आ रही है, मगर ऐन मौके पर गेंद मिडिल स्टंप पर दिखती है। भारत के शिवराम कृष्णन की तरह कादिर को भी काफी सफलता मिली है।

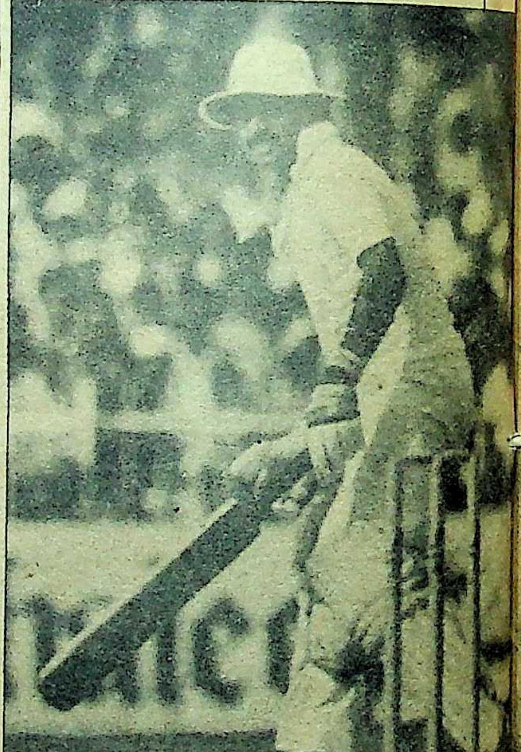

नियंत्रित हमला : जावेद मियांदाद छाया : सुनील सक्सेना

बहरहाल, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, लोगों की अपेक्षाओं को हमेशा पूरा करना मुश्किल होता है, पाकिस्तान के लिए भी रिलायंस कप एक चुनौती साबित होगा। अपने पूल में उसे भारी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ेगा। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड अपनी पुरानी उपलब्धियों को दोहराना चाहेंगे। क्या पता घरेलू दर्शकों की तेज आवाजें उन्हें इतने तनाव में डाल दें कि वे सेमीफाइनल में भी न पहुंच पायें। बेशक उनमें जीतने की पूरी काबिलियत है, मगर एक दिवसीय क्रिकेट में भाग्य भी बहुत मायने रखता है।

—अनिल शर्मा

सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, आस्ट्रेलिया

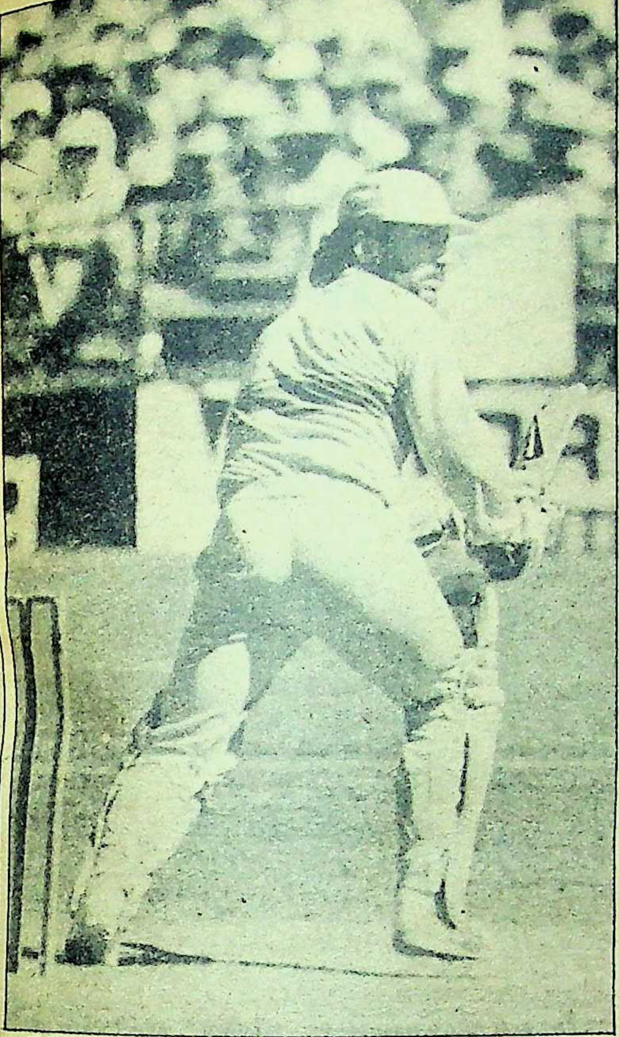

समर्पित कप्तान: एलेन बार्डर

वाल्फ

छाया: विमल सक्सेना

भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें पश्चिम से आ रही उन टीमों पर भी टिकी होंगी, जो इस चोटी की क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश में यहां आ रही हैं। खास तौर पर कपिल और उसके साथी आस्ट्रेलियाई टीम का वजन तौलने में लगे होंगे जो एक वर्ष के भीतर दूसरी बार इस उपमहाद्वीप में क्रिकेट दौरे पर आ रही है। पिछले दौरे के मद्रास और बंबई के मैचों में उन्होंने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। उस दौरे के बाद उनके उत्साह में भी वृद्धि हुई होगी, लेकिन चिदंबरम स्टेडियम के ऐतिहासिक टाई मैच और वानखेड़े स्टेडियम में कांटे की टक्कर की यादें इंग्लैंड के दौरे ने धोकर रख दी हैं। विश्व कप में आस्ट्रेलिया अपनी योग्यता और सम्मान को फिर से पाने की कोशिश करेगा।

समर्पित कप्तान और शानदार बल्लेबाज एलेन बार्डर ने आस्ट्रेलियाई टीम को संवारने की भरपूर कोशिश की है, मगर कैरी पैकर के अभिशाप से टीम को अभी तक उबार नहीं पाये हैं। बेंसन ऐंड हेजेज कप के अलावा कोई बड़ी सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। १९७५ के विश्व कप का फाइनल खेलने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन दिनो-दिन गिरता चला गया। १९७९ और १९८३ के विश्व कप में नौबत यहां तक पहुंच गयी कि वह सेमी फाइनल तक पहुंचने से भी वंचित हो गयी। ऐसा कैरी पैकर के सर्कस के चलते हुआ, जिसमें उसने आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को खरीद लिया था। १९७७ से १९७९ तक चले इस सर्कस ने आस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में कई असफलताएं जोड़ दीं। अच्छे खिलाड़ियों के तैयार न हो पाने से आज हालत यह हो गयी है कि कोई उसे घास नहीं डालता। अपनी जमीन पर कदाचित उसे कुछ सफलताएं मिलीं लेकिन कुल मिलाकर उसका रिकार्ड खराब ही रहा। १ जनवरी, १९७७ के बाद खेले गये ५२ टेस्ट मैचों में उसने केवल ६ जीते हैं, जबकि २३ में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी २२ ड्रा रहे और एक मैच 'टाई' पर छूटा। इसी प्रकार एक दिवसीय मैचों में भी उसका रिकार्ड कुछ खास नहीं रहा है। १७५ एक दिवसीय मैचों में से उसने ७८ जीते हैं और ८७ में उसे पराजय मिली। इसके अलावा एक मैच टाई और नौ अधूरे छूटे हैं। यानी जीत का औसत ४७.४२ प्रतिशत रहा।

आस्ट्रेलियाई अधिकारियों को सबसे ज्यादा दुख हाल ही में संपन्न दो प्रतियोगिताओं में मिली हार से हुआ है। १९८५ में विक्टोरिया राज्य की १५०वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विश्व चैंपियनशिप में तथा उसके बाद इसी साल पर्थ में आयोजित चार देशों की सीमित ओवर प्रतियोगिता में आस्ट्रेलियाई टीम फिसड्डी साबित हुई।

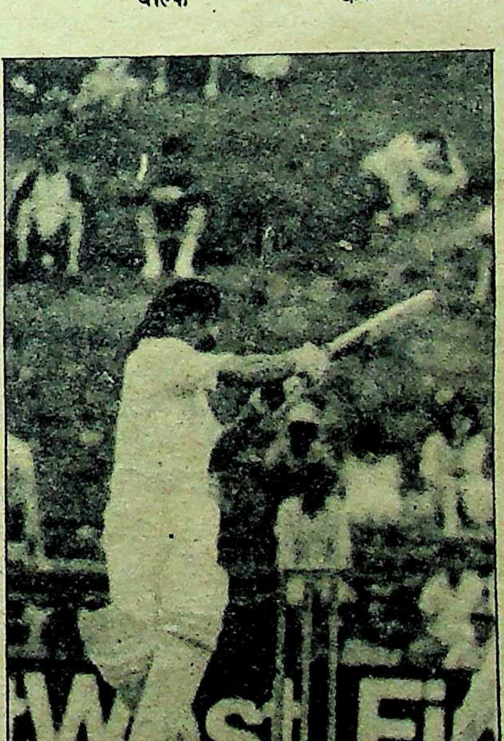

शानदार बल्लेबाज: डेविड बून

बहरहाल, आस्ट्रेलियाई टीम कम-से-कम सेमी फाइनल में पहुंच सकती है, क्योंकि उसे आसान 'ग्रुप' मिला है। इस ग्रुप में उसके अलावा भारत, न्यूजीलैंड और जिबाब्वे हैं। यदि वह भारत से हार भी जाती है, तो न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। हालांकि भारत का, सेमीफाइनल में पहुंचना तय मानकर लोग दूसरे नंबर के लिए मुख्य संघर्ष न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के बीच ही मान रहे हैं, मगर अभी कुछ कहना मुश्किल है।

भारत में आस्ट्रेलिया का एक दिवसीय रिकार्ड अच्छा रहा है। कुल आठ मैचों में से पांच उसने जीते हैं, जबकि भारत ने केवल तीन में ही विजय हासिल की है। पिछले साल भारत-आस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय सिरीज में भारत ३-२ से जीता था। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के खिलाफ हारने के बावजूद आस्ट्रेलिया की जीते मैचों की संख्या ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब न्यूजीलैंड का प्रमुख खिलाड़ी रिचर्ड हैडली नहीं आ रहा है, तो इसका फायदा आस्ट्रेलिया और भारत दोनों को मिलेगा। यहां तक कि १९८३ के विश्व कप में आस्ट्रेलिया को हराने वाला जिबाब्वे भी इसे गंभीरता से लेगा।

आस्ट्रेलियाई टीम का मुख्य दारोमदार कप्तान एलेन बार्डर और सलामी बल्लेबाज डेविड बून के कंधों पर रहेगा। (नये खिलाड़ियों में हरफनमौला टाम मूडी, सीम बालर एंड्रू जेसर्स और आफ स्पिनर टिम मे के उल्लेखनीय नाम हैं।

—माइक कावर्ड

इंग्लैंड का पलड़ा भी भारी है

अब्बास अली बेग

British Caledo

परख की बारी: इंग्लैण्ड -क्रिकेट टीम के खिलाड़ी

इंग्लैंड का पिछली सर्दी में आस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन उसके लिए राहत की बात थी। जिस समय पर्थ में चैलेंज सीमित ओवर वाला टूर्नामेंट समाप्त हुआ, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इंग्लैंड विश्व की बेहतरीन टीमों का मुकाबला करने में फिर सक्षम हो गया है। उसकी यह प्रसन्नता स्वाभाविक थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले दौरे पर आयी उन टीमों से उसे अपने ही मैदानों पर मुंह की खानी पड़ी थी, जिन्हें वह हिकारत की नजर से देखती थी। किंतु तमाम विषमताओं के बावजूद जब शरजाह में इस गरमी में उसने विजय हासिल की, तो उसकी पूर्व की विफलताएं विस्मृत कर दी गयीं।

शरजाह को मिली विजय विशेष तौर पर सराहनीय थी, क्योंकि अनेक धुरंधरों की अनुपस्थिति ने इंग्लैंड को सबसे निचली श्रेणी में ला खड़ा किया था। यह जीत संपूर्ण विषमताओं में उसकी अडिगता, उसके धैर्य, कौशल और पेशेवराना महारत का प्रतिफल थी। रिलायंस कप में उसका दावा भी काफी मजबूत है, बशर्ते दो चीजें आड़े न आयें—(१) ग्रीष्म टैस्ट शृंखला में पाकिस्तान से मिली पराजय की पस्तहिम्मती (२) टीम में बाथम और गावर की गैर मौजूदगी।

बहरहाल पाकिस्तान से पराजय टैस्टों की शृंखला में मिली थी। सीमित ओवर की शृंखला के उत्साहजनक परिणामों से इंग्लैंड संतोष कर सकता है। किंतु टेक्सको ट्राफी की जीत में उनकी टीम में सभी सितारे खिलाड़ी थे। अब वे दो अनुभवी और विश्वसनीय खिलाड़ी उनके साथ नहीं होंगे। क्या इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा? काफी समय से गावर और बाथम दोनों अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। गावर थका-मांदा लगता था और अपनी अनवरता व्यस्तता से विश्राम का हकदार था। बाथम उस दैत्य की छाया भर लगने लगा है, जिसने क्रिकेट संसार को अपनी अचूक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से चौंकाये रखा था। लगता है क्रिकेट से इतर विषयों का बोझ भी उसके दिमाग पर है और एक खिलाड़ी (वह बाथम ही क्यों न हो) जो अपना सर्वस्व अर्पित नहीं करता, (वस्तुत: भार) टीम और उसके प्रबंधक के लिए एक परेशानी बन जाता है।

यह रवैया युवा और अति संवेदनशील टीम सदस्यों के लिए एक बुरी मिसाल और साथ ही पस्तहिम्मती पैदा करता है। इसलिए आधे मन से तैयार बाथम की अपेक्षा पूर्ण समर्पित डी फ्रेटास या कापल को चुना जाना चाहिए। खासकर जहां संघर्ष मात्र ५० ओवर तक सीमित है।

डी फ्रेटास ने अपनी फार्म फिर पा ली है। आस्ट्रेलिया में आक्रामक 'सीम बालर' और एक उपयोगी तीव्र प्रहारक बल्लेबाज की भूमिका उसने निभायी थी। कापल अपनी काउंटी के लिए और यहां तक कि पाकिस्तान के विरुद्ध सीमित ओवर के मैचों में बहुत अच्छा खेलता रहा है। ये दोनों आशान्वित होंगे और बड़ी हस्तियों की अनुपस्थिति से उपलब्ध अवसर को हथियाना चाहेंगे। इसी प्रकार गावर की अनुपस्थिति एथी और अन्य युवाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेगी।

जीत के लिए गंभीर: माइक गैटिंग

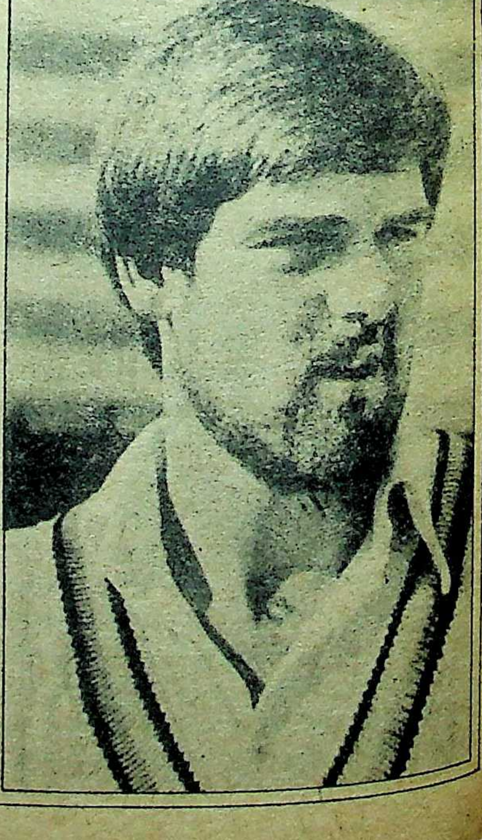

विस्फोटक बल्लेबाज एलन लैंब को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसका रिकार्ड भी सीमित ओवर के मैचों में सराहनीय रहा है। गूच की वापसी भी महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में वह बहुत उपयोगी रहेगा। डिली और फास्टर ने पर्याप्त महारत हासिल कर ली है और वे दुर्जेय सिद्ध होंगे। डी फ्रेटास, कापल और स्माल विल उन्हें भरपूर सहयोग देंगे। एम्बुरी घातक 'आफ-स्पिन' करेंगे और गैटिंग तथा गूच भी 'शार्ट स्पेल्स' से सहायता कर सकते हैं। मध्यक्रम बल्लेबाजी की कमान जहां प्रशंसनीय तिकड़ी ब्राड, राबिसन, एथी के हाथों होगी वहीं उनकी अग्रिम पंक्ति के योद्धा होंगे—गूच व लैंब।

गैटिंग को अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी में स्थान बनाने में काफी सफर तय करना पडा है। इमरान के खिलाफ दो शतक उसकी योग्यता के प्रमाण हैं। इसलिए इंग्लैंड को महज इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके दो असाधारण खिलाड़ी अनुपस्थित रहेंगे। उनकी जीत की संभावना अभी भी उतनी ही अच्छी है।

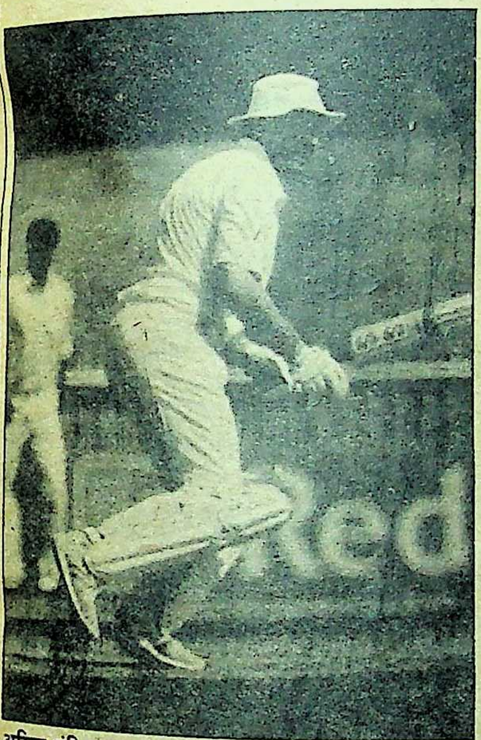

अग्रिम पंक्ति का योद्धा : ग्राहमगूच

कुछ भी हो एक दिवसीय क्रिकेट के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। समझदार टीम तेज-तर्रार, किंतु तुनक मिजाज लोगों की टीम की टक्कर में चतुरता से खेलकर विजयी हो सकती है।

मिकी स्टीवर्ट का क्रिकेट मैनेजर के रूप में टीम पर पूर्ण नियंत्रण है और आशा है दौरे पर आने वाली टीम के वह सरपरस्त होंगे जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। एक लंबे समय का दौरा बहुत अधिक अकेलेपन का अहसास पैदा कर सकता है। विशेषकर यदि आप घर से दूर हों। इंग्लैंड की टीम अपने अधिकांश ग्रुप मैच पाकिस्तान में खेलेगी जो उसकी मुसीबतें और बढ़ा सकती है, क्योंकि वहां की पिचें तेज गेंदबाजों की सहायता नहीं करतीं। अतः उन्हें सही गेंदबाजी और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण पर निर्भर रहना पड़ेगा। उनकी पेशेवराना महारत और सीमित ओवर की स्थितियों का अनुभव उनको अतिरिक्त लाभ पहुंचायेगा।

—अब्बास अली बेग

क्या वेस्टइंडीज तीसरी बार विश्व कप जीतेगा ?

सफल कप्तान : क्लाइव लायड

१९७५ और १९७९ के पहले दो प्रुडेंशियल विश्व कप में वेस्टइंडीज को सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कैलिप्सो संगीत के बादशाहों ने कोई भी मैच गंवाये बिना दोनों ट्राफियां जीत लीं। १९८३ में वेस्टइंडीज की टीम विश्व विजय की हैट्रिक (तिकड़ी) पूरी करने को तत्पर थीं, पर भारत की अविस्मरणीय जीत ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विश्व कप में कोई भी मैच न हारने वाली टीम को उस टीम ने हरा दिया, जिसने १९८३ से पहले के दो विश्व कपों में केवल एक मैच जीता था। रिलायंस कप अब चौखट पर आ खड़ा हुआ है, लिहाजा सवाल उठा है कि क्या वेस्टइंडीज पिछली हार का बदला लेगा ?

सुनील गावस्कर से जब हाल में पूछा गया कि रिलायंस कप प्रतियोगिता में उन्हें किस टीम के जीतने की संभावना दिखायी देती है, तो उन्होंने बिना हिचके जवाब दिया, "निश्चित रूप से वेस्टइंडीज की।"

१९८३ में कपिल देव के साथियों द्वारा की गयी धुलाई के बाद स्थितियां काफी बदल गयी हैं। वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा सफल तत्कालीन कप्तान अब रिटायर हो गये हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि वह लायड ही थे, जिन्होंने वेस्टइंडीज के प्रतिभाशाली, मगर रास्ते से भटके (वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के लिए अकसर यही विशेषण इस्तेमाल किया जाता है) खिलाड़ियों को सही दिशा देकर विश्व विजेता टीम में ढाला। नतीजतन, एक दिवसीय क्रिकेट में श्रेष्ठता का प्रतीक प्रुडेंशियल विश्व कप खिताब उसने दो बार जीता।

लायड का व्यक्तित्व बहुत मेधावी था। उन्हें अपनी टीम के साथियों का भरपूर सम्मान और सहयोग मिला। उन्होंने हमेशा खुद अच्छा प्रदर्शन कर, दूसरों के लिए मिसाल पेश की। जैसे हर अच्छी चीज दीर्घजीवी नहीं होती, उसी तरह लायड की विश्व विजेता टीम भी अपराजेय नहीं रही। १९८३ के प्रुडेंशियल कप में और १९८५ की विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज की हार ने साबित कर दिया कि अब स्थितियां पहले जैसी अच्छी नहीं रही हैं। वजह साफ है। वेस्टइंडीज को जीत दिलाने वाले तेज गेंदबाज जो महज अपनी रफ्तार से विपक्षी टीम को ध्वस्त कर देते थे, श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच कर ढलने लगे थे। उनकी जगह तत्काल नये गेंदबाजों को लाने की जरूरत थी।

वेस्टइंडीज को लायड जैसा कप्तान अभी तक नहीं मिल सका हैं। रिचर्ड्स साथियों में आत्मविश्वास भरने में सफल नहीं हो पाये हैं। एक कप्तान के नाते उनका प्रदर्शन भी कमजोर रहा है। पाकिस्तान के विरुद्ध अनिर्णीत खतम हुई टैस्ट सिरीज के बाद एक दिवसीय मैचों की सफलता ने कैरेबियन क्रिकेट पर छाये काले बादलों में उम्मीद की किरण चमकायी है। सबसे उल्लेखनीय सफलता वेस्टइंडीज को पिछले साल शरजाह में मिली, पर बेंसन ऐंड हेजेज अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सिरीज में उसे हार मिली। १९७९ में यह यह सिरीज शुरू हुई थी और इससे पहले जब भी वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, उसने फाइनल जीता था, पर इस साल के शुरू में कैलिप्सो के बादशाह पहली बार बेंसन ऐंड हेजेज प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच पाये।

१९८३ के विश्व कप में वेस्टइंडीज की जो टीम खेली थी, उसमें माइकल होल्डिंग, लैरी गोम्स, क्लाइव लायड, एंडी राबर्ट्स और कोई विशेष प्रतिष्ठा न पा सकने वाले फाउद बैकस का नाम नहीं है। ये पांचों खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ चुके हैं। इससे एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। मैल्कम मार्शल, जोएल गारनर

और गोर्डन ग्रीनिज के न होने से रिचर्ड्स की टीम अब तक के विश्व कप में हिस्सा लेने वाली सबसे कमजोर टीम बन गयी है।

हाल में कैरेबियन टीम का प्रदर्शन गड़बड़ाया, तो इसलिए कि तेज गेंदबाजों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मार्शल ने स्वीकार किया है कि सामान्यत: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों को हर स्तर के क्रिकेट में औसतन हर साल करीब एक हजार ओवर फेंकने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। स्वाभाविक है कि इससे उनकी ऊर्जा का क्षरण हुआ है।

हालांकि यह हलके-फुलके अंदाज में कहा जाता है कि "कैरेबियन में अगर आप एक पेड़ को हिलायें, तो दर्जनों के हिसाब से गेंदबाज झड़ेंगे, लेकिन यह तय है कि रिलायंस कप में वेस्टइंडीज की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि नये गेंदबाज कैसा खेल दिखा पाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज गेंदबाजों की नयी पौद होल्डिंग, राबर्ट्स, मार्शल और गारनर जैसी क्षमता वाली नहीं है और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। टीम में अब सिर्फ एक ही अनुभवी तेज गेंदबाज रह गये हैं और वह हैं—विंस्टन डेविस। वह राबर्ट्स, गारनर, होल्डिंग और मार्शल के साथ खेल कर काफी अनुभव हासिल कर चुके हैं। लेकिन ३० साल पार करने की वजह से उनका पैनापन जाता रहा है।

वेस्टइंडीज की रणनीति उसके तेज गेंदबाजों की सफलता पर निर्भर करती है। वह लायड ही थे, जिन्होंने १९७५-७६ में अपमानजनक हार झेलने के बाद 'ईंट का जवाब ईंट' और 'खून के बदले खून' की योजना व नीति बनायी थी। भारत के खिलाफ तत्काल बाद की सीरिज में स्पिनरों पर उनका भरोसा उस समय टूट गया, जब उनके स्पिनर ४०३ रन पास होने के बावजूद मेहमान टीम को आउट कर उसे ऐतिहासिक जीत पाने से नहीं रोक सके। लायड ने सबक सीखा। वह जान गये कि तूफानी गेंदबाज ही विपक्षी टीम को ध्वस्त कर सकते हैं। अपनी योजना को पूरी दृढ़ता से लागू करने का श्रेय लायड को देना ही होगा। वह हमेशा प्रतिद्वंद्वी के खेमे में जाकर लड़ते थे। मध्यम तेज गेंदबाज होल्डर और जूलियन की जगह उन्होंने टीम में डायनामाइट भर लिए। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को वह यह समझा पाने में सफल रहे कि सही मायने में थोक के हिसाब से तेज गेंदबाज तैयार करके ही प्रतिष्ठा पायी जा सकती है।

बेहतर कप्तान साबित होने का मौका: रिचर्ड्स

डूजान

कोलिन क्राफ्ट और जोएल गारनर का उदय नाटकीय था और उस परंपरा का हिस्सा था, जो उस समय कैरेबियन में चल रही थी। अगर १९७७ का क्रिकेट सीजन शुरू होने से पहले कोई गंभीरता से भी कहता कि क्राफ्ट और गारनर नाम के लंबे गेंदबाज जिन्हें क्रमश: 'एयरक्राफ्ट' और 'बिग बर्ड' कहा जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम के महत्वपूर्ण सदस्य साबित होंगे, तो इस बात को कोरी गप या हवाई उड़ान कह कर टाल दिया जाता।

गारनर और क्राफ्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तो बात दूर रही, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट का भी मामूली अनुभव था। लेकिन खिलाड़ियों के घायल होने का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला शुरू हुआ कि इन दो नौसिखिए गेंदबाजों को मौका मिल गया, फिर तो वे लगातार सफलता प्राप्त करते गये।

क्या वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की नयी पौध उसी तेजी और उतनी ही चतुराई से गेंद फेंक पायेगी जैसी १९७७ में क्राफ्ट और गारनर ने फेंकी थी? यह अहम सवाल है। धीमी और बेजान भारतीय पिचें संभवत: वेस्टइंडीज का संकट और बढ़ायेंगी। ये विपरीत परिस्थितियां वेस्टइंडीज के पैनेपन को और भोथरा कर सकती हैं।

लेकिन एक बात वेस्टइंडीज के पक्ष में कही जा सकती है और वह यह कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय उसके जैसे क्षेत्ररक्षक और किसी टीम में नहीं हैं। गली में रिचर्ड्स, रिचर्डसन और हार्पर, शार्ट लेग में हेंस कैसा भी कैच लपकने में माहिर हैं। जबकि बाकी युवा खिलाड़ी और ज्यादा सतर्क व चुस्त हैं—खासतौर से रन बचाने के मामले में। वे गेंद नपे तुले अंदाज में वापस करते हैं और किसी भी कोण से सीधे विकेट बिखेर सकते हैं। यह पक्ष आक्रमण में जुड़ जाने के बाद नतीजा यही निकलता है कि पलड़ा वेस्टइंडीज के पक्ष में झुका हुआ है।

हाल के वर्षों में कैरेबियन बल्लेबाजी चिंता का कारण बनी है। तेजतर्रार क्रिकेट खेलने वाले गोर्डन ग्रीनिज की आतिशी बल्लेबाजी और चुस्त क्षेत्ररक्षण इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ग्रीनिज के विकल्प को चुनने में चयनकर्ता भी संकट में पड़ गये। संभावना यही है कि उभरते हुए बल्लेबाज एंटीगुआ के रिची रिचर्डसन का क्रम बदल कर उन्हें हेंस के साथ पारी शुरू करने भेजा जाये। हेंस ने फटाफट क्रिकेट में अधिकतम नौ शतकों का रिकार्ड रिचर्ड्स के साथ बना रखा है।

इस बात पर भी काफी कुछ निर्भर करता है कि गेंद को पूरी ताकत से हिट करने वाले रिचर्ड्स कैसी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले कुछ सालों से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी उन्हीं पर केन्द्रित है। अगर वह नाकाम होते हैं, तो अकसर पूरी टीम लुढ़क जाती है।

कैलिप्सो के बादशाह स्वाभाविक खेल खेलते हैं। गेंद को ताकत से मारना, तेज गेंदबाजी, फुर्तीला क्षेत्ररक्षण और कलाबाजी खाकर कैच लपकना कैरेबियन क्रिकेट की विशेषता है। जाहिर है ऐसी प्रतिभाशाली टीम को अनदेखी करना मूर्खता होगी।

पिछले प्रुडेंशियल कप में कमजोर भारतीय टीम से वेस्टइंडीज के हारने के बाद जान वुडकाक ने कैरेबियन क्रिकेट की क्षमताओं की बहुत अच्छी व्याख्या की थी। 'विसडन' (खेल पत्रिका) में वेस्टइंडीज की हार पर वुडकाक ने लिखा, "लार्ड्स में वेस्टइंडीज की हार ने मुझे एलेक्स बैनिस्टर के कथन की याद दिला दी। बेनिस्टर ने एक बार वेस्टइंडीज क्रिकेट के बारे में कहा था— "वेस्टइंडीज अद्वितीय टीम है और उसकी एकमात्र ताकत उसका बिखराव ही है।" इसी से पूरी स्थिति साफ हो जाती है।

—रवि चतुर्वेदी

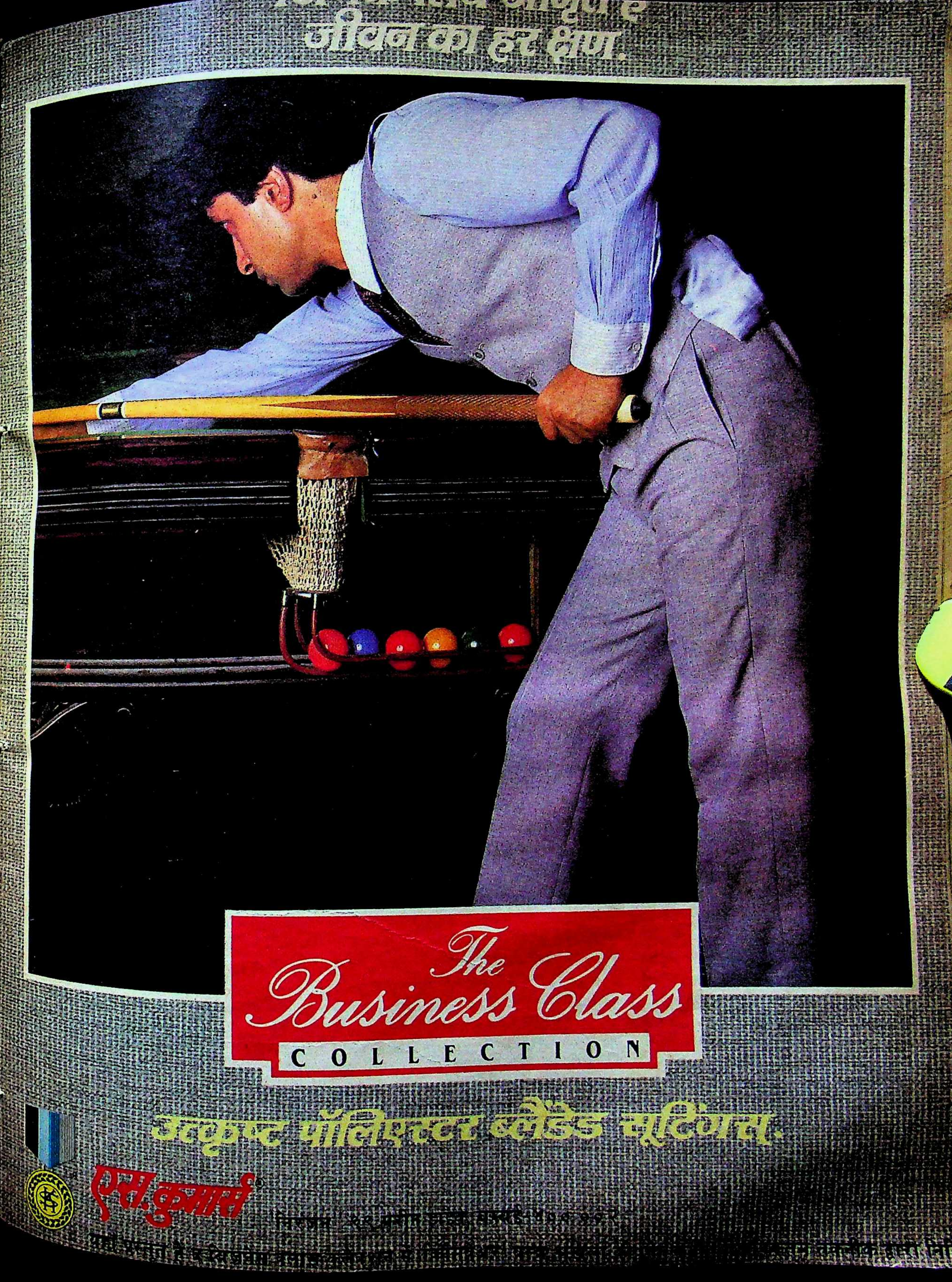
जीवन का हर क्षण.
The Business Class
COLLECTION
उत्कृष्ट पॉलिएस्टर ब्लैंडेड सूटिंग्स.
एस.कुमार्स

क्या भारत यह कप जीत पायेगा ?

56

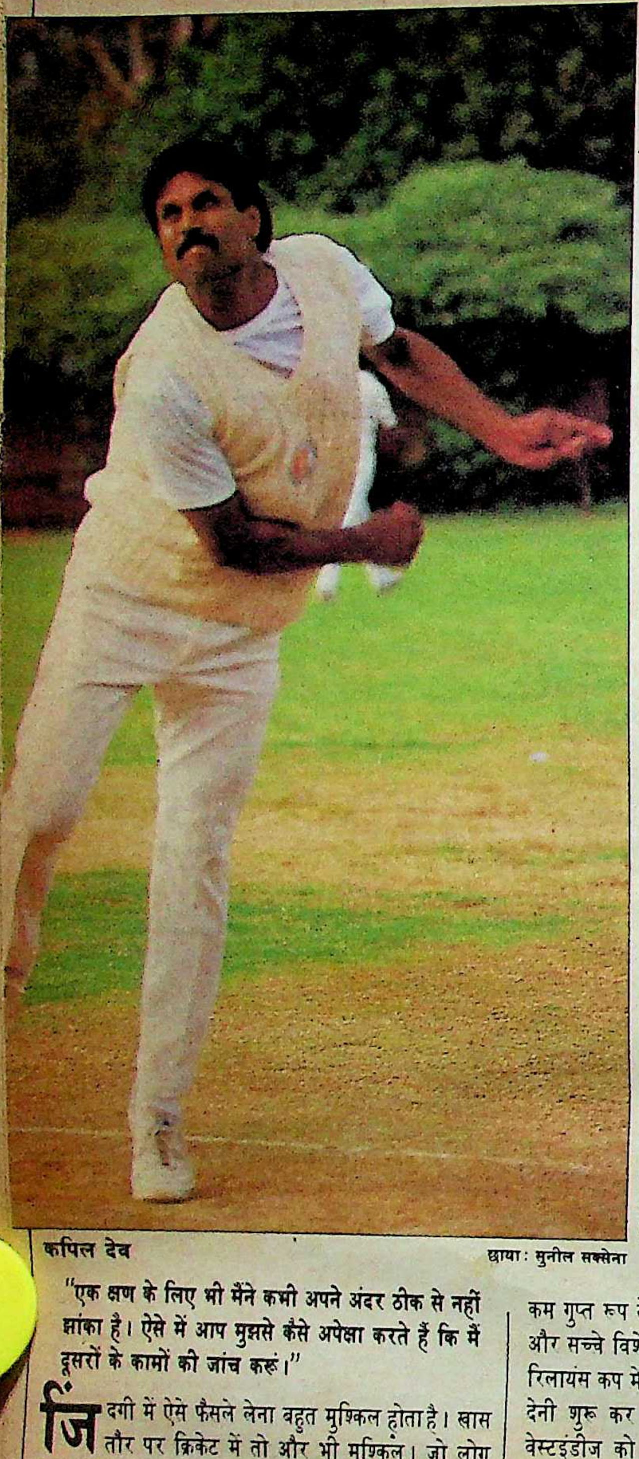

कपिल देव छाया : सुनील सक्सेना

"एक क्षण के लिए भी मैंने कभी अपने अंदर ठीक से नहीं झांका है। ऐसे में आप मुझसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि मैं दूसरों के कामों की जांच करूं।"

जिंदगी में ऐसे फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर पर क्रिकेट में तो और भी मुश्किल। जो लोग क्रिकेट के खेल से परिचित हैं, वे जानते हैं कि इसमें कुछ भी पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इस खेल में भविष्यवाणियां बहुत कम ही सफल हुई हैं। लेकिन यह क्रिकेट की खूबी ही कही जायेगी कि यह लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए उकसाता है और फिर उन्हें झूठा साबित कर देता है। अकसर केवल अनुमान के आधार पर अपने दोस्त से बाजी लगाने वालों की बातें सच निकल जाती हैं और अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करनेवाला विशेषज्ञ झूठा साबित हो जाता है। 'विशेषज्ञ के साथ सबसे बुरी बात यही है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि वह विशेषज्ञ है।'

दरअसल, क्रिकेट को जानने और समझने वाला हर व्यक्ति स्वयं में भी एक विशेषज्ञ होता है या यह गुण कम-से-कम गुप्त रूप से उसके दिल में तो होता ही है। ऐसे विशेषज्ञ और सच्चे विशेषज्ञों ने भारत और पाकिस्तान में शुरू हो रहे रिलायंस कप में विभिन्न टीमों की संभावनाओं पर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। खिताबधारी भारत और उपविजेता वेस्टइंडीज को अलग-अलग 'ग्रुपों' में रखा गया है। ड्रा के अनुसार अपने ग्रुप में भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है। उसके ग्रुप में पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही आस्ट्रेलिया, सितारों की अनुपस्थिति से कमजोर न्यूजीलैंड और नौसिखिया जिबाब्वे है। जिबाब्वे ने आई०सी०सी० ट्राफी जीतकर विश्व कप में भाग लेने की योग्यता हासिल की थी। दूसरे ग्रुप में वेस्टइंडीज के सामने सभी तगड़ी टीमें हैं और एक भी मैच को वह हलके ढंग से नहीं ले सकती। पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों टीमें अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई हैं। इसके अलावा श्रीलंका भी उसी के ग्रुप में है।

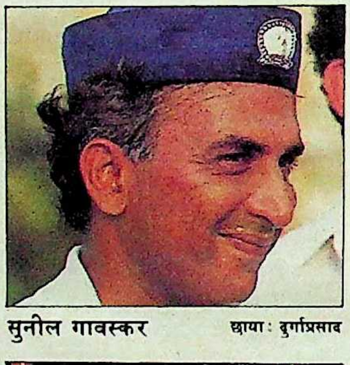

सुनील गावस्कर छाया : दुर्गाप्रसाद

इमरान खां छाया : दुर्गाप्रसाद

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कुछ लोगों की उठापटक से भारतीय टीम की तैयारियों को दोहरा झटका लगा है। बोर्ड की राजनीति के चलते संभावित खिलाड़ियों की सूची समय पर घोषित नहीं हो सकी। ऐसा बोर्ड के उस वाहियात और अनावश्यक फैसले के कारण हुआ, जिसके द्वारा पूरी चयन समिति ही बदल दी गयी। नयी चयन समिति के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह संभावित खिलाड़ियों का नाम जांच परख के बाद घोषित करे। २५ सभावित खिलाड़ियों की सूची भी पुरानी चयन समिति द्वारा चुनी गयी। लेकिन शायद यही पर्याप्त नहीं था। बोर्ड ने टीम के तीन सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए उदयपुर का चुनाव करके एक और बड़ी भूल की।

सैर करने की दृष्टि से उदयपुर एक अच्छा स्थान हो सकता है, मगर प्रशिक्षण शिविर के लिए आदर्श जगह तो वह कतई नहीं है। एक कालेज ग्राउंड का बाहरी ढांचा निश्चित ही अच्छा हो सकता है, पर उसकी मिट्टी का परीक्षण होना भी जरूरी है। वहीं की पिच में स्पिन तो बहुत है, लेकिन बाउंस बिलकुल नहीं। फिर ऐसी पिच पर अभ्यास का क्या मतलब, जहां रिलायंस कप का एक भी मैच न खेला जाना हो। खिलाड़ियों की मांग ने भी उक्त बात की पुष्टि कर दी है और अब वे राष्ट्रीय खेल संस्थान, दिल्ली द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट हैं। बहरहाल, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मेहरबानी से भारतीय खिलाड़ियों का कीमती समय तो नष्ट हो ही गया। कहीं जाकर २६ सितंबर को भारत ने अपनी चौदह सदस्यीय दल की घोषणा की।

गावस्कर, श्रीकांत, वेंगसरकर, शास्त्री, मनिंदर, अजहर और कपिल टीम की धुरी होंगे। मोरे और पंडित में से किसी एक को चुना जायेगा। हालांकि विकेट कीपिंग के लिहाज से मोरे ज्यादा बेहतर हैं। चेतन शर्मा का चयन उनके स्वास्थ्य पर निर्भर है। १९८३ के विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रोजर बिन्नी के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। भारतीय परिस्थितियों में उनका रिकार्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। मनोज प्रभाकर के मुकाबले उनके अवसर फीके रहेंगे, क्योंकि क्योंकि प्रभाकर एक दिवसीय मैचों में शतक बना चुके हैं और सुबह (नौ बजे) उनकी स्विंग गेंदबाजी उपयोगी साबित हो सकती है। शिवराम कृष्णन के चुने जाने का स्वागत होना चाहिए। देवधर ट्राफी में शिवा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वह 'अपने दिन' मैच जिताने वाले सिद्ध हो सकते हैं। खास तौर पर न्यूजीलैंड और जिबाब्वे के खिलाफ। वह एक अच्छा बल्लेबाज और चुस्त क्षेत्ररक्षक भी हैं।

दिल्ली में लगे कैंप में कप्तान कपिल देव, उप कंप्तान वेंगसरकर, मैनेजर मान सिंह और कोच वासु परांजपे ने अपना

पूरा ध्यान गेंदबाजी पर लगाये रखा। दो दिन की भागदौड़ के बाद चेतन शर्मा अपने रंग में आ गये। कम-से-कम उन्होंने अपनी फिटनेस तो सिद्ध कर ही दी। इससे कप्तान कपिल देव का तनाव थोड़ा कम हुआ होगा। वहां उपस्थित टीम के ज्यादातर सदस्यों के अनुसार शिव राम बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। हालांकि कुछ समय पहले उनके आत्मविश्वास में कमी आयी थी, लेकिन अब सभी को यह विश्वास है कि अच्छे प्रदर्शन के जरिये वह उसे फिर प्राप्त कर लेंगे। कुछ पुराने खिलाड़ियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि 'लड़के' को अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। स्पिनर्स और उस पर भी लेग स्पिनर को 'सही मारक क्षमता' हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कपिल, शास्त्री और मनिंदर, भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ होंगे, जबकि शिवा और चेतन भारतीय जीत के नायक बन सकते हैं। अपने मैदानों पर भारतीय टीम को दर्शकों की ओर से पूरा समर्थन मिलेगा। इसकी एक वजह सुनील गावस्कर भी होंगे, क्योंकि पहले दर्जे के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रिलायंस कप में वह आखिरी बार हिस्सा लेंगे। टेस्ट क्रिकेट में ढेरों रिकार्ड और महान सफलताएं हासिल करने के बावजूद एक दिवसीय मैचों में गावस्कर उतने 'महान' कभी नहीं हो पाये। हकीकत तो यह है कि पिछले तीन विश्व कपों में अपने प्रदर्शन को वह शायद ही याद करते हों। हाल में लार्ड्स के पांच दिवसीय मैच में लगाये शानदार शतक की तरह एक दिवसीय मैच में भी शानदार प्रदर्शन करके सिद्ध कर सकते हैं कि उनमें अभी भी वैसा ही दमखम और टाइमिंग बाकी है। जाहिर है इसके लिए रिलायंस कप से बेहतरीन अवसर और क्या हो सकता है। हां, गावस्कर सभी की आशा के केंद्र होंगे और हम जानते हैं कि उनमें इसकी अकूत क्षमता भी है।

कुल मिलाकर देखा जाये, तो भारत को सेमीफाइनल में अवश्य पंहुचना चाहिए। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्रुप 'ए' से सेमीफाइनल में पहुंचने के दूसरे दावेदार होंगे। जिबाब्वे के लिए यह सिद्ध करने का सुनहरा मौका है कि अब वह भी टेस्ट खेलने वाले देशों में शामिल होने के लायक हो गया है।

भारतीय टीम का सेमीफाइनल के आगे पहुंचना कुछ भाग्य और कुछ उस दिन के खेल पर निर्भर है। घरेलू मैदानों में भारतीय टीम का एक दिवसीय मैचों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान द्वारा ५-१ से रौंदे जाने के बाद संदेह है कि भारत दूसरी बार यह ट्राफी जीत पायेगा। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल है। १९८३ के प्रुडेंशियल कप में सेमीफाइनल तक पहुंच जाने के बाद भी कोई यह नहीं सोच रहा था कि भारत विजेता बनेगा। भारत की मुख्य समस्या यह है कि घरेलू पिचों में बाउंस और घुमाव न होने के कारण उसके गेंदबाज सफलता से कोसों दूर रहे। १९८३ के विश्व कप और १९८५ में आस्ट्रेलिया में गेंदबाजों की सफलता का एकमात्र कारण यही था कि वहां उन्हें अनुकूल पिचें मिलीं। भारत को एक धुआंधार बल्लेबाजी (जैसे पाकिस्तान का वासिम अकरम) करने वाले एक खिलाड़ी की भी जरूरत है। ऐसे में वह अपनी चुनौती को तभी बरकरार रख सकता है, जब मुश्किल से मुश्किल कैच को भी न छोड़ा जाये और रन रोकने में पूरी टीम एक मशीन-की तरह एकजुट हो जाये।

पर्थ में चैलेंज कप और इंग्लैंड में टैक्सको ट्राफी में हार (दोनों जगह इंग्लैंड से) तथा अपने ग्रुप में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद पाकिस्तान के आसार सबसे बढ़िया हैं। इसके लिए कारण ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। घर में पाकिस्तान का रिकार्ड हमेशा अच्छा रहा है। पिछले तीनों विश्वकपों में वह सेमीफाइनल तक पहुंचा था। इस सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल में इंग्लैंड और भारत के खिलाफ मिली विजय से टीम के हौसले बुलंद हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का फायदा भी उसे मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास सबसें बढ़िया कप्तान भी है। दृढ़ निश्चयी इमरान ने अपनी योग्यता कई मौकों पर सिद्ध की है। अपने शानदार व्यक्तित्व और प्रदर्शन के जरिये उन्होंने लगभग अनुभवहीन टीम को जीतने की स्थिति में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान के पक्ष में दांव लगाने वाले जुआरियों की संख्या से पाक की स्थिति साफ समझ में आती है। लेकिन प्रतियोगिता की शुरुआत में ही ऐसा समर्थन और अपेक्षाएं उसके लिए तनाव का कारण बन सकती हैं।

माइक गैटिंग

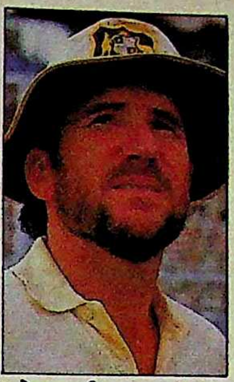

एलेन बार्डर छाया: सी० एन० एस०

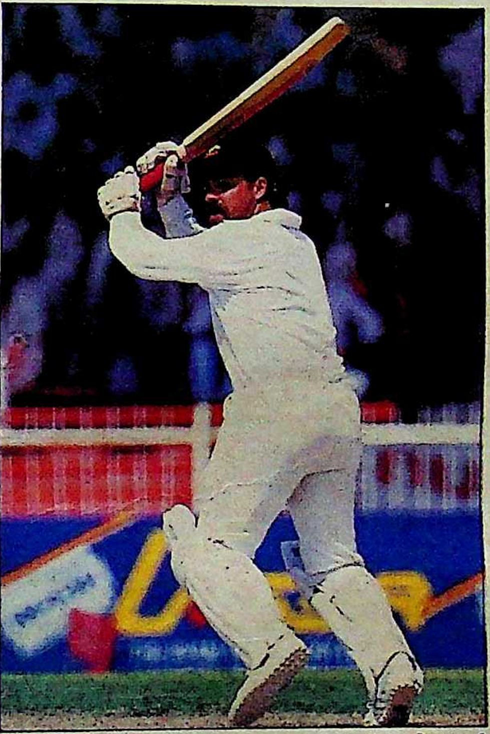

डेविड बून छाया: प्रदीप मंघानी

गोम्स, होल्डिंग (दोनों रिटायर) ग्रीनीज, गार्नर और मार्शल की गैर मौजूदगी के बावजूद वेस्टइंडीज की चुनौती को अनदेखा नहीं किया जा सकता। रिचर्ड्स और हेंस विश्व के सफल बल्लेबाजों में से हैं। मगर पाकिस्तान की तरह उसकी भी बैटिंग एक ही बल्लेबाज रिचर्ड्स पर निर्भर है। ग्रे, वाल्श, बेंजामिन, डेविस और बाप्टिस्ट अन्य अच्छे खिलाड़ी हैं। ये मार्शल, होल्डिंग और गार्नर के मुकाबले में कहीं नहीं बैठते, मगर उनके मुकाबले के गेंदबाज तो किसी भी टीम में नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर अनुभवी और पेशेवर हैं तथा इस तरह का (एक दिवसीय) खेल खेलने के आदी हैं। इंडीज के भी सेमीफाइनल में पहुंचने के आसार अच्छे हैं।

गूंच, ब्राड, राबिंसन, एथी, गैटिंग और लैंब जैसे मजबूत बल्लेबाजों से सजी इंग्लैंड की परीक्षा भी भारत की तरह गेंदबाजी में ही होगी। पर्थ और शरजाह जैसे आश्चर्यजनक परिणाम लाने में इंग्लैंड भी आगे है। दो विश्व-स्तरीय खिलाड़ी बार्डर और मार्टिन की उपस्थिति के बावजूद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चुनौती को कोई खास नहीं समझा जा रहा है। न्यूजीलैंड ने हैडली के बिना आज तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। हैडली के भाग न लेने के फैसले के बाद कोनी और हावर्थ ने भी रिटायरमेंट ले लिया था। नतीजतन टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की बेहद कमी है। वे ज्यादा-से-ज्यादा सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आस्ट्रेलिया भी संकट के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय से उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि डेढ़ साल पहले 'बेंसन ऐंड हेजेज कप' में उसने भारत और न्यूजीलैंड को पछाड़ा था। अपने पिछले दौरे में भी वह भारत के लिए सिरदर्द साबित हुआ था। जोकर किंतु प्रतिभाशाली खिलाड़ी ग्रेग मैथ्यूज, जोरदार प्रहार करने वाले ग्रेग रिची और वेन फिलिप्स की अनुपस्थिति के बावजूद आस्ट्रेलिया सेमीफाइनल का प्रमुख दावेदार होगा।

मगर श्रीलंका और जिबाब्वे किस पायदान पर होंगे? साफ-साफ कहा जाये, तो तमाम संभावनाएं और सामर्थ्य के बावजूद इनके स्तर में अभी उतना सुधार नहीं हुआ है कि उन्हें गंभीरता से लिया जाये। दोनों टीमों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, मगर किसी अनसोचे परिणाम की उम्मीद नहीं बनती।

३० सितंबर को प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में खेले गये मैच में मिली विजय भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पिछले कई मैचों में लगातार पाकिस्तान के हाथों पराजित होने के कारण भारतीय टीम का आत्मविश्वास और मनोबल टूटता नजर आ रहा था। लेकिन इस 'दिन-रात' के मैच में पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हुए हैं। इस मैच में भारतीय टीम की सबसे बड़ी खूबी यह नजर आयी कि १९८३ के प्रुडेंशियल की भांति वह फिर 'एक टीम' की तरह खेली। गेंदबाजी कमजोर होने के बावजूद चुस्त क्षेत्ररक्षण ने उसे संभाले रखा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने कप्तान और बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी इमरान की गैरमौजूदगी में यह मैच खेला था। इसलिए इस सुनहरी जीत के बावजूद आगे के मैचों में पाकिस्तान पर भारतीय टीम भारी पड़ेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

कुल मिलाकर मुकाबले कांटे के होंगे। यह पहला मौका है, जब प्रतियोगिता संतुलित है। कोई भी एक टीम ऐसी नहीं है, जिसे पूरे विश्वास के साथ विजेता कहा जा सके। वह तो प्रुडेंशियल कप ही था, जिसमें हर बार पहले से कह दिया जाता था कि वेस्टइंडीज की टीम जीतेगी और दो बार वह जीती भी। बहरहाल, हर क्षण उत्तेजना में डूबा रहेगा रिलायंस कप का। एक डाक्टर की तरफ से मुफ्त सलाह है कि अपने दिल और खून को काबू में रखें। वैसे यदि आप दिल या ब्लड प्रेशर के मरीज हों, तो मुझसे संपर्क करें।

—डा० नरोत्तम पुरी

सायमन्ड्स

क्रिकेट का बेहतरीन साजो सामान.

BOMBER
POWER DRIVER
SYMONDS
Symonds
ALL ROUNDER
SYMONDS

जी. ग्रीनिज

बिल एथे

जी. मैथ्यूज़ / एस.वॉग

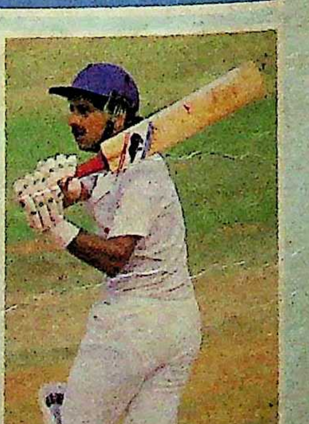
के. श्रीकांत

सायमन्ड्स बैट–बने हैं असली रबराइज़्ड पॉली से, जो अन्य कोई निर्माता इस्तेमाल नहीं करता

बिक्री व्यवस्था : ए.एच. व्हीलर एंड कं. प्रा. लि., २३ एल.बी. शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद २११ ००१

Mechanix-779HIN

फरदून डी वित्रे

मीडिया : जिम्मेदारी और चुनौतियां

ऐसा नहीं है कि भारतीय मीडिया को रिलायंस विश्व कप जितनी बड़ी खेल स्पर्धा को इससे पहले संभालने का मौका नहीं मिला। कुछ मिसालें दिमाग में आती हैं। १९८२ में अविस्मरणीय रूप से सफल एशियायी खेल हुए। रिलायंस कप में तो सिर्फ आठ देशों के ११२ क्रिकेट खिलाड़ी ही आ रहे हैं, जबकि एशियायी खेलों में ३५ देशों के पांच हजार से ज्यादा खिलाड़ी आये थे। इसके बाद कलकत्ता और नयी दिल्ली में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई, बंबई में विश्व कप हाकी हुई।

पर रिलायंस विश्व कप को जो बात इन स्पर्धाओं से अलग करती है, वह है इसका फैलाव। अब १७ मैच १४ अलग-अलग केन्द्रों पर होने हैं। केन्द्र भी एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि कहां दक्षिण में बेंगलौर और कहां पूरब में कटक। इसके पूर्व बाकी सभी बड़ी प्रतियोगिताएं एक ही शहर में हुईं, इसलिए खासतौर से मीडिया को ऐसी चुनौती का पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा।

दूरदर्शन ने इस चुनौती को सिर माथे लगाने का फैसला किया है। छह ओ०बी० (बाह्य प्रसारण) वैन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने विशेष रूप से रिलायंस कप के लिए बनायी हैं। चार ओ०बी० वैन दूरदर्शन के पास पहले से हैं। इन सभी वैनों में आधुनिकतम उपकरण लगे हैं। कैमरों में ८०० मिलीमीटर के जूम लैंस हैं जो शायद बी०बी०सी० तक ने किसी क्रिकेट कवरेज के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किये हैं। 'जेनो' पद्धति है। यह कंप्यूटरीकृत है और इसमें खिलाड़ियों के अलग-अलग एक्शन की तस्वीर टेलीविजन सेट के एक कोने में साथ-साथ दिखायी देती है। तीन अलग-अलग कैमरा कोणों से तत्काल एक्शन रिप्ले दिखाने के लिए तीन वी०सी०आर० (वीडियो टेप रिकार्डर) वैन में हैं।

काफी विचार-विमर्श के बाद दूरदर्शन ने एक ही सिरे से कैमरा कवरेज करने के बी०बी०सी० के तरीके को अपनाने का फैसला किया है। दोनों सिरों पर कैमरा लगाने की आस्ट्रेलिया के चैनल नौ की शैली को छोड़ दिया गया है। बी०बी०सी० शैली में यह सुविधा है कि दर्शक को ऐसा लगता है मानो स्टैंड की बेहतरीन सीट से साफ-साफ मैच देख पा रहा हो। वैसे भी पास में छह कैमरे होने की वजह से दूरदर्शन के सामने इस पद्धति को चुनने के सिवाय और कोई बेहतर विकल्प नहीं था।

भारत में पहली बार सभी केन्द्रों पर कैमरा लगाने की जगहों का मानकीकरण कर दिया गया है, जैसे—पहला कैमरा ग्राउंड लेबल पर लांग आफ पर होगा। दूसरा और तीसरा कैमरा एक दूसरे से करीब ४० फुट की ऊंचाई पर गेंदबाज के पीछे लगेगा। चौथा कैमरा ग्राउंड लेबल पर होगा और छठा ४० फुट की ऊंचाई पर। दोनों मिड विकेट पर होंगे। 'स्लो मोशन' दिखाने के लिए पांचवां कैमरा दूसरे और तीसरे कैमरे से बिलकुल विपरीत दिशा में रहेगा। धीमी रफ्तार में 'एक्शन रिप्ले' इन छह में से तीन कैमरों से देखे जा सकेंगे।

सभी उपकरण अच्छे, उपयोगी और दुरुस्त हैं, लेकिन उन्हें संभालनेवाले लोग? इसके लिये जून में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इस वर्कशाप में निर्माण, तकनीक और शाट लेने के तौर-तरीकों को मानकीकृत करने में मदद मिली है। टीम की अवधारणा पहली बार भारत में प्रयोग की जा रही है। हर प्रोडक्शन युनिट का एक बॉस यानी प्रोड्यूसर होगा, कंट्रोल रूम में मानीटर पर उसके सामने छह तस्वीरें होंगी। उसे ही यह चुनना होगा कि कब, किस तस्वीर को खतम कर उसकी जगह दूसरी तस्वीर दिखायी जाये। अक्सर प्रोड्यूसर की गलती का दोष असहाय कैमरामैन पर थोप दिया जाता है, जैसे—प्रोड्यूसर किसी नाजुक मौके पर विकेट के आसपास की गतिविधियां दिखाने की बजाय भीड़ पर घूमते शाट को दिखा दे तो इसके लिये कैमरामैन दोषी नहीं। लेकिन कभी-कभी प्रोड्यूसर भी कैमरामैन को जिल्लत से बचाता है। ठीक तरह फ्रेम में नहीं आये या फोकस से बाहर रह गये शाटों को वह इस्तेमाल नहीं करता, इससे साबित होता है कि हर टेलीविजन कवरेज मुख्य रूप से टीम-वर्क है। हर प्रोडक्शन टीम का नेतृत्व क्रिकेट कार्यक्रमों के देश के तीन बेहतरीन प्रोड्यूसर विजय कुमार (दिल्ली), पी०वी० सतीश (हैदराबाद) और अभिजीत दास गुप्ता (कलकत्ता) करेंगे। चौथी टीम के नेता एस०वी० शर्मा होंगे, जो अलग से मुख्य अंशों का कामकाज देखेंगे।

इन टीमों का एक विशेष अंग है, आखों देखा हाल सुनाने वाले कमेंटेटर। "टाइगर" पटौदी हर मैच के एक घंटे के खास-खास अंश प्रस्तुत करेंगे। इस काम के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। पटौदी कम बोलते हैं पर उनका सारगर्भित विश्लेषण खासा असर डालता है।

अन्य लोगों में तीन भूतपूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं—बिशन सिंह बेदी, एम०एल० जयसिम्हा और अब्बास अली बेग। इसके अलावा नरोत्तम पुरी और मैं खुद भी इस काम में शामिल रहूंगा। अनुपम गुलाटी, वेंकटसुंदरम और सुनील गुजराल जैसे युवा धुरंधर भी हैं। हिंदी की कमेंट्री रवि चतुर्वेदी और सुशील दोषी के काबिल हाथों में होगी।

टी०वी० कमेंटेटर पर आमतौर पर आरोप लगाया जाता है कि वे बोलते ज्यादा हैं, मगर अक्सर यह आधारहीन होता है। टीवी विशेष रूप से देखने का माध्यम है। यहां आवाज दूसरे नंबर पर आती है। साफ तस्वीर खुद बोलती है और उसमें किसी और को बोलने की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत तस्वीर अगर खराब होगी और काफी दूर दिखाई देगी तो इस खामी को दूर करने के लिये ज्यादा बोलने की जरूरत तो पड़ेगी ही।

रेडियो के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहां माइक पर बैठे व्यक्ति को शुरू से आखिर तक पूरी भूमिका खुद निभानी पड़ती है। बिना टीवी कमेंटेटर के तो फिर भी तस्वीर और परिचयांकन (कैप्शन) से पूरी कहानी बतायी जा सकती है पर रेडियो कमेंटेटर के बिना तो प्रसारण ही नहीं हो सकता। रेडियो कमेंटेटर स्टेडियम के बाहर फैले लोगों के लिये खेल की तस्वीर गढ़ता है।

रिलायंस कप के लिए आकाशवाणी ने दो दिग्गज लोगों—अनंत सीतलवाड़ और सुरेश सरैया को अपनी टीम का मुखिया बनाया है। जे०पी० नारायणन, प्रदीप विजयकर व विजयन बाला जैसे कमेंटेटर भी हैं। पर लोग शानदार कमेंटेटर मेजर श्रीनिवास नारगोलकर की आवाज सुनने से वंचित रहेंगे। हिंदी कमेंटरी के लिए स्कंद गुप्त, जोगाराव, मनीष देव और स्थूलकाय व हसमुख राजेन्द्र मल्होत्रा जैसे अनुभवी लोग हैं।

अब मीडिया के चौथे खंभे प्रेस की बात की जाये। बहुत से मैच हो रहे हैं, इसलिए उन्हें कवर करना सभी के लिए कई मायने में मुश्किल काम हो जायेगा। वे दिन संपादक के लिए मुश्किल के होंगे जब तीन मैच एक साथ खेले जा रहे होंगे। यह फैसला उसे जल्दी करना होगा कि अपने विशेष संवाददाता को भेजे या एजेंसियों पर निर्भर करे। यह ऐसा अवसर है कि प्रमुख अखबार अपने संवाददाता भेजना पसंद करेंगे, बशर्ते प्रेस बाक्स में जगह कम न पड़े।

आशंका है कि जगह की कमी कहीं विवाद की वजह न बन जाए। बताया जाता है कि "आई०पी०जे०एम०सी०" (भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोजन समिति) ने प्रेस बाक्स में उपलब्ध सीटों का ५० प्रतिशत विदेशी संवाददाताओं को अलाट करने का फैसला किया है। भारतीय प्रेस के लोगों को जिस बात से धक्का लगा है (और यह स्वाभाविक भी है) वह यह कि विदेशों से आने वाले मीडिया के लोगों में सबसे ज्यादा संख्या सिर्फ एक देश इंगलैंड की है। वहां से ६० लोग आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान में खेले जाने वाले मैच कवर करेंगे। इंगलैंड वर्ग "ब" के अपने दो मैच ही भारत में—जयपुर और पुणे में खेलेगा। बाकियों में आस्ट्रेलिया से सात, न्यूजीलैंड से तीन, वेस्टइंडीज और श्रीलंका से दो-दो संवाददाता आयेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे से जरूर कोई नहीं आ रहा लेकिन बंबई के सेमीफाइनल और कलकत्ता के फाइनल को कवर करने के लिये तो पाक संवाददाता आयेंगे ही, ऐसी स्थिति में विदेशी संवाददाताओं के लिए ५० फीसदी सीटों का आरक्षण भारतीय संवाददाताओं के साथ किसी भी तरह न्याय नहीं है।

संवाददाताओं के लिये आशाजनक बात यह है कि हर मैदान में टेलेक्स मशीन लगायी जा रही है, पर आनेवाली संवाददाताओं की भीड़ पर ध्यान दिया जाये तो दो और तीन मशीनें पर्याप्त नही होंगी। यह दृश्य अक्सर दिखाई देगा कि कोई संवाददाता बड़ी व्यग्रता के साथ सी०टी०ओ० की यह मंजूरी पाने का इंतजार कर रहा है, कि उसकी कापी भेज दी गयी है। खास तौर से कानपुर, नागपुर और अहमदाबाद में यह समस्या होगी।

—फरदून डी वित्रे

फ्रेडी के नाम से विख्यात फरदून डि वित्रे पेशे से वकील हैं। नम्र स्वभाव के जिंदादिल फ्रेडी हरफन मौला खिलाड़ी थे। संचार माध्यमों का उन्हें लंबा अनुभव है। न केवल टी०वी० कमेंट्रेटर और प्रस्तुतकर्ता की हैसियत से, बल्कि बंबई टी०वी० के प्रोड्यूसर की हैसियत से भी उन्हें जन माध्यमों के हर पेच की जानकारी है। वह एक अच्छे पत्रकार हैं और आकाशवाणी से भी काफी अरसे तक जुड़े रहे हैं। रिलायंस कप में वह भी दूरदर्शन पर अंग्रेजी में कमेंट्री करेंगे।

संभावनाएं नौसिखिया टीमों की

मौजूदा फार्म और पिछली प्रतिष्ठा को देखते हुए श्रीलंका और जिम्बांब्वे को सीमित ओवर की रिलायंस विश्वकप प्रतियोगिता की नौसिखिया या सबसे कमजोर टीम मानना होगा। सटोरियों और आम क्रिकेट प्रेमियों की राय में इन दोनों देशों के प्रतिष्ठित रिलायंस कप जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये टीमें आखिरी पायदान पर खड़ी होने के बावजूद कोई अच्छी सफलता भी पा सकती हैं। १९७९ और १९८३ के प्रुडेंशियल विश्वकप की तरह अगर इनमें से कोई भी टीम अप्रत्याशित जीत प्राप्त कर लेती है, तो दूसरी टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो जायेगी।

श्रीलंका विश्वकप में नया नहीं है। पिछली तीनों प्रतियोगिताओं में उसने हिस्सा लिया है। इस बार वर्ग "ब" में उसे वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और इंगलैंड के साथ रखा गया है। यह तय है कि श्रीलंका के सामने मुश्किल चुनौती है। सेमीफाइनल में पहुंचना तो अलग रहा, एक मैच भी जीत पाना उसके लिए मुश्किल काम होगा।

लेकिन श्रीलंका में अप्रत्याशित नतीजा लाने की क्षमता है। यह याद रखें कि एक दिवसीय क्रिकेट में एक ही दिन में कमाल दिखाना होता है। लिहाजा अनिश्चितता की स्थिति टेस्ट मैच और दूसरे स्तर के क्रिकेट के मुकाबले एक दिवसीय क्रिकेट में ज्यादा रहती है।

पिछले विश्व कप मैचों का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि श्रीलंका ने हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों को परेशान किया है। १९७५ के पहले विश्व कप में श्रीलंका ने इयान चैपल की मजबूत आस्ट्रेलियाई टीम को, लिली और थामसन जैसे महान तेज गेंदबाजों की मौजूदगी के बावजूद जीत के लिए तरसा दिया था। ११ जून को ओवल में यह मैच खेला गया। आस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की धुंआधार शुरूआत की। सलामी खिलाड़ी एलन टर्नर ने १०१ और रिक मैकास्कर ने ७३ रन बना कर पहले विकेट के लिए ११८२ रन का रिकार्ड बनाया। करीब १० साल बाद १९८५ में रवि शास्त्री और श्रीकान्त ने इंगलैंड के खिलाफ कटक में इस रिकार्ड को तोड़ा। आस्ट्रेलिया ने ६० ओवर में ५ विकेट पर ३२८ रन जुटा लिए, पर तारीफ की बात यह रही कि श्रीलंका ने जवाब में घुटने नहीं टेके। थामसन की गेंदों पर वेट्टीमुनि और मेंडिस के चोट खा जाने के बावजूद श्रीलंका ने ४ विकेट पर २७६ रन का प्रशंसनीय स्कोर खड़ा कर लिया। श्रीलंका के पहले सात खिलाड़ियों ने दहाई की संख्या पार की। सलामी खिलाड़ी वेट्टीमुनि और एम०एच० निसेदा ने अर्द्धशतक बनाए। श्रीलंका हारा पर इस हार में भी सम्मान था।

अशांत डी मेल और लेबराय

चार साल बाद श्रीलंका ने विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की। भारत के खिलाफ खेलते हुए १६ जून को ओल्ड ट्रेफर्ड (मानचेस्टर) में श्रीलंका की टीम सही तालमेल से खेली और ६० ओवर में ५ विकेट पर २३८ रन बना लिए। सलामी खिलाड़ी वेट्टीमुनि ने ६७ और मौजूदा कप्तान दलीप मेंडिस ने रन आउट होने से पहले ६४ रन बनाए। भारत ने बड़े घटिया अंदाज में बल्लेबाजी की और वह अपने हिस्से के पूरे ६० ओवर तक भी क्रीज पर नहीं टिक सका। ५४.१ ओवर में भारतीय टीम १९१ रन पर ही उखड़ गयी। तेज गेंदबाज टोनी ओपाथा ने ३१ रन पर ३ विकेट लिये और लेग स्पिनर डी०एस० डीसिल्वा ने २९ रन पर तीन विकेट।

१९८३ के विश्व कप में भी १८ जून को डर्बी में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड पर तीन विकेट से अप्रत्याशित जीत पायी। दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज असांत डी मेल ने बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी करते हुए १२ ओवर में ३२ रन देकर पांच विकेट लिये और न्यूजीलैंड को १८१ रन पर चलता कर दिया। इस मामूली स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम शुरू में थोड़ा लड़खड़ाई पर राय डायस के ६४ नाबाद रन की मदद से उनके ५२.५ ओवर में ७ विकेट पर १८४ रन बन गए। श्रीलंका की इस अप्रत्याशित जीत ने न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के आसार चौपट कर दिए। इसी तरह १९८७ के रिलायंस कप में भी श्रीलंका की टीम किसी मजबूत टीम को हराकर सारे समीकरणों को उलट-पलट सकती है।

श्रीलंका में जातीय हिंसा और तनाव के चलते रिलायंस विश्व कप के लिए क्रिकेट टीम की तैयारियों पर असर पड़ा। रिलायंस कप के लिए उसे अभ्यास दिलाने के वास्ते आस्ट्रेलियाई टीम को श्रीलंका बुलाया गया था। लेकिन श्रीलंका की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को देखकर आस्ट्रेलिया ने यह दौरा रद्द कर दिया था। इससे श्रीलंका की टीम को खासतौर पर निराशा हुई, क्योंकि उसके खिलाड़ियों को पर्याप्त अभ्यास का मौका नहीं मिल पाया।

रिलायंस कप के लिए श्रीलंका की टीम संतुलित है। असांत डी मेल, रवींद्रन (रवि) रत्नायके और रुमेश रत्नायके के रूप में श्रीलंका के पास अच्छा मध्यम तेज गति का आक्रमण है। क्रिकेट प्रेमियों को रवि रत्नायके का नाम याद होगा, जिसने १९८६ में कानपुर में खेले गए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में १२ रन पर ३ विकेट लेकर भारतीय पारी को ध्वस्त कर दिया था। क्रिसमस से एक दिन पहले हुए इस मैच में भारतीय टीम का २४.१ ओवर में ७६ रन पर ही बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। श्रीलंका ११७ रन से यह मैच जीती थी। इस जीत को कप्तान दलीप मेंडिस ने अपनी टीम की सर्वश्रेष्ठ जीत बताया।

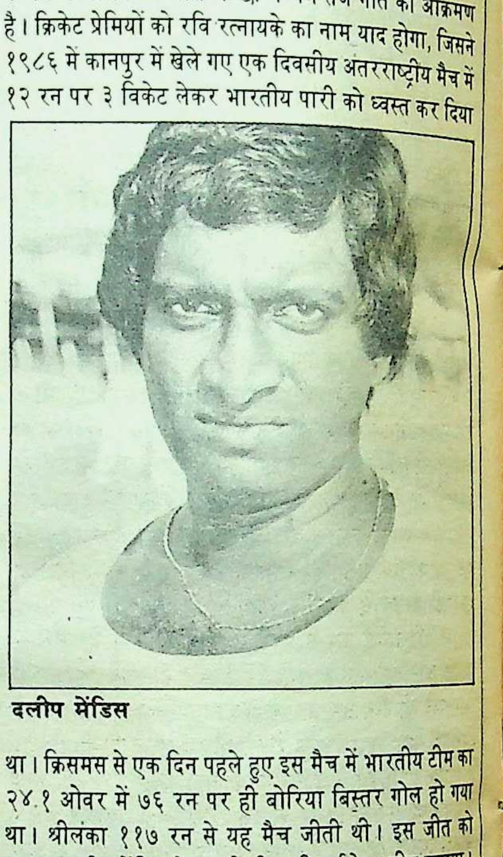

दलीप मेंडिस

श्रीलंका की बल्लेबाजी में सूक्ष्मदर्शिता और मजबूती का तालमेल है। कप्तान दलीप मेंडिस और १९८२-८३ में भारत के खिलाफ एक दिवसीय मैचों की सिरीज में नयी दिल्ली में १०२ व बंगलौर में १२१ रन बनाने वाले राय डायस जुझारू बल्लेबाज हैं जो तेजी से और ज्यादा रन बना सकते हैं। सलामी खिलाड़ी रोशन महानामा ने १९८६-८७ की एक दिवसीय सिरीज में भारत के खिलाफ बंबई में ९८ रन बनाए थे। खब्बू खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगे एक दिन के ५० मैच खेल चुके हैं और एक उपयोगी मध्यम गति के तेज गेंदबाज भी हैं। १९८६-८७ में कानपुर में भारत के खिलाफ गेंदबाजी का उनका सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण रहा था—१४ रन पर ४ विकेट, इन दोनों के अलावा विकेट कीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन कुरुप्पू भी अच्छे स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। श्रीलंका को वर्ग "ब" के अपने ज्यादातर मैच पाकिस्तान में ही खेलने हैं, लेकिन उसके दो मैच भारत में भी होंगे। २१ अक्तूबर को श्रीलंका कानपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ और ३० अक्तूबर को इंगलैंड के खिलाफ पुणे में खेलेगा। श्रीलंका कोशिश करेगा कि अपने छह लीग मैचों में कम से कम एक अप्रत्याशित जीत पाने का सिलसिला तो बनाए ही रखे।

जिम्बाब्वे ने पहली बार १९८३ में इंगलैंड में विश्व कप खेला था। खाफी मजबूत टीमों के साथ उसे जगह मिली थी। उसके वर्ग में पिछली विजेता वेस्टइंडीज की टीम के अलावा भारत और आस्ट्रेलिया की टीमें थी। इसके बावजूद जिम्बाब्वे की टीम अपनी प्रतिद्वंद्वी टीमों की प्रतिष्ठा से हड़बड़ाई नहीं। विश्व कप में जिम्बाब्वे का प्रवेश यादगार रहा। ९ जून को टेंट ब्रिज (नार्टिघम) में उसने आस्ट्रेलियाई टीम को १३ रन से हरा कर चौंका दिया।

कप्तान डंकन फ्लैचर ने पहले इंगलिश काउंटी ग्लूस्टर-शायर के लिए खेलने वाले केबिन करेन के साथ १५ ओवर में ७० रन जोड़े और फिर इयान बूचर्ट के साथ १२ ओवर में ७५ रन बनाए। किम हयूज की कप्तानी में खेल रही आस्ट्रेलियाई टीम मैदान में आश्चर्यजनक रूप से निस्तेज रही। उसने पांच कैच छोड़े। जिम्बाब्वे ने अपने निर्धारित ६० ओवर में ६ विकेट पर २३९ रन बनाये। जवाब में आस्ट्रेलियाई टीम ढह गई। सलामी खिलाड़ी कैपलर वैसल्स के ७६ और विकेट कीपर रॉडनी मार्श के नाबाद ५० रनों के बावजूद, ६० ओवर में वह ७ विकेट पर २२६ रन ही बना सकी।

बाद में भी जिम्बाब्वे के लिए प्रतिष्ठा के पल आए। १८ जून को टेंट ब्रिज में एक समय जिम्बाब्वे ने भारत को १३ ओवर में ५ विकेट पर १७ के स्कोर तक घिसटा दिया। मध्यम गति के तेज गेंदबाजों रासन और करेन ने यह नुकसान किया। भारत संभला तो कपिल देव के तूफानी और अविजित १७५ रन की वजह से जो आज भी विश्व कप का सर्वोच्च स्कोर है। भारत ने २६६ रन जमा किए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम २३५ रन तक पंहुच पायी। केविन करेन ने ७३ और सलामी खिलाड़ी आर डी ब्राउन ने ३६ रन बनाए।

रिलायंस कप में जिम्बाब्वे वर्ग "अ" में आस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड के साथ है। १९८३ की तरह इस बार भी जिम्बाब्वे की टीम क्षेत्ररक्षण के लिहाज से विलक्षण होगी। सभी खिलाड़ी गोता लगाकर रन रोकने और मैदान के किसी भी छोर से सटीक थ्रो फेंकने में माहिर हैं। कप्तान जान ट्रेकास दाएं हाथ के उपयोगी बल्लेबाज और आफ ब्रेक गेंदबाज हैं। १९६९-७० में आस्ट्रेलिया के खिलाफ वह तीन टेस्टों में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले थे। वह सिरीज दक्षिण अफ्रीका ने ४-० से जीती थी।

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी में शामिल हैं—पीटर रासन, केविन करेन और ई ब्रेंडेज। तीनों १९८३ के विश्व कप में भी खेल चुके हैं। उन पर भरोसा किया जा सकता है और अगर मनमाफिक परिस्थितियां मिलीं तो वे किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं।

जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को लेकर थोड़ा संशय जरूर है। १९८३ के विश्व कप में कप्तान रहे डंकन फ्लैचर और युवा हिक को उसे खोना पड़ा है। दोनों ने फैसला किया है कि वे इंगलैंड के लिए खेलनें की कोशिश करेंगे। लेकिन २१ साल के केविन अर्नाट (जिन्होंने १९८६-८७ में पाकिस्तान की 'बी' टीम के खिलाफ लगातार अच्छा स्कोर किया है) और २५ साल के मुहम्मद अहमद मेमान "बाबू" से अच्छे खेल की उम्मीद की जाती है। विकेट कीपर-बल्लेबाज डेविड हाफरन भी भरोसे के बल्लेबाज हैं। उसने १९८३ में आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा ८४ रन बनाए थे। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम विश्वकप की सबसे कमजोर टीम रहेगी तो भी वह वर्ग "अ" के एक दो मैचों में ऐसा उलटफेर तो कर ही सकती है जो सेमीफाइनल का समीकरण ही बदल दे।

—नोवी कपाड़िया

टीम का चयन कैसे होता है ?

लोगों की नजर में चयनकर्ता चाहे जोकर या विदूषक जैसी चीज भले ही हो, मगर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक संतुलित टीम का चयन निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। देखा जाये तो यह क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण मसलों में से एक है। चयनकर्ता जैसी टीम चुनेंगे, परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। अगरचे उनकी इस कार्यवाही से जहां कुछ लोग खुश होते हैं, तो कुछ मीन-मेख निकालने में जुट जाते हैं।

१९८५ में जब राष्ट्रीय चयन समिति के लिये मुझे चुना गया, तो मुझे यह बड़ा दुष्कर कार्य लगा, क्योंकि हाल्ल ही (१९८४) मैंने राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ली थी। दिल्ली क्रिकेट अधिकारियों से मतभेद होने की वजह से मैंने ऐसा किया था। मेरा चयन अचानक हुआ था, जिससे इस चुनौती से निपटने के लिये मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया। चयनकर्ता के रूप में दो वर्ष के कार्यकाल में मुझे ढेर सारे अनुभव मिले।

टीम चुनने के लिये जो तरीके अपनाये जाते हैं, उनसे सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उन पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मगर कुछ बातें साफ की जानी जरूरी हैं जिससे इस प्रक्रिया के बारे में कोई शक-शुबहा न रहे। एक बात तो बिलकुल साफ और सुनिश्चित है कि चयन समिति की बैठक के दौरान चाहे जितना बहस-मुबाहिसा हो, लेकिन एक बार जब फैसला ले लिया जाता है, तो वह पूरी समिति का फैसला होता है और उसकी जिम्मेदारी हर सदस्य पर बराबर होती है। गरमागरम बहस से उपजा तनाव बैठक सम्पन्न होने के बाद कमरे की चार दीवारों के अंदर दफन कर दिया जाता है।

चयन के दौरान हुए विवाद को गुप्त रखना चयनकर्ताओं के लिये एक अलिखित कानून होता है। टीम के चुनाव के पहले किसी प्रकार की टीम संबंधी सार्वजनिक घोषणा करना भी निषिद्ध है। ऐसा करना गोपनीयता भंग करने के दायरे में ही आता है। आमतौर पर टीम का एक प्रारूप पहले तैयार कर लिया जाता है और फिर उसके हिसाब से खिलाड़ियों का चयन होता है। लेकिन किसी विदेशी दौरे के लिये टीम का चयन करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानद सचिव चयन समिति को फोन या पत्र द्वारा सूचित करता है कि फलां मैच या श्रृंखला के लिये टीम का चयन करना है, इसलिए फलां तारीख को फलां जगह उपस्थित हों। कंट्रोल बोर्ड का मानद सचिव चयन समिति का पूर्व सदस्य और बैठक का संयोजक होता है। वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं होता। बैठक के बाद वह प्रेस को नयी टीम के बारे में जानकारी देता है।

कप्तान के चयन का निर्णय समिति की पहली बैठक में ही ले लिया जाता है। उम्मीदवारों के दावों के कमजोर और मजबूत दोनों पक्षों पर बहस होती है। यह भी देखा जाता है कि वर्तमान कप्तान टीम को एकजुट रखने में कितना सक्षम है। यदि विचार-विमर्श के बाद एकमत से फैसला नहीं होता तो फिर मतदान होता है। लेकिन यदि मतदान से भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता, तो अध्यक्ष का मत निर्णायक भूमिका अदा करता है। १९७१ में वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने वाली टीम के लिये विजय मर्चेंट ने अपने मत से पटौदी की जगह अजीत वाडेकर को कप्तान बनाया था। कप्तान चुना जानेवाला खिलाड़ी भी फिर चयन समिति में शामिल कर लिया जाता है। टीम के चुनाव के लिये उससे सलाह-मश्विरा तो लिया जाता है, मगर उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। यदि टीम का चुनाव किसी विदेशी दौरे के लिये होना हो, तो फिर बगैर मतदान के अधिकार के कप्तान और मैनेजर दोनों चयन समिति में शामिल रहते हैं। यदि किसी मामले में चयनकर्ताओं में मतभेद होता है, तो फिर कप्तान से राय मांगी जाती है। यद्यपि यह संभव है कि कप्तान की राय से कमेटी के सदस्य सहमत हो जायें, मगर राय देने से ज्यादा अधिकार कप्तान को नहीं होता। लेकिन इससे प्रेस को अटकलें लगाने का मौका मिल जाता है। गावस्कर का मामला गौर के काबिल है। अपनी कप्तानी के दौरान गावस्कर की राय पर बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वह चयनकर्ताओं को समझाकर अपने पक्ष में करने में होशियार थे। लेकिन जब टीम हार जाती है, जैसा पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत को भारत और शरजाह दोनों जगह हराया, तो शोर मचने लगता है। सबसे पहली मांग तो यही होती है कि कप्तान बदलो। बदकिस्मती से हार को कप्तान की अक्षमता का परिचायक माना जाता है। यदि ऐसा है, तो जब टीम विजयी होती है, (पुडेंशियल कप और विश्व चैंपियन शिप कप) तो सम्मान सभी सदस्यों में क्यों बांटा जाता है?

मगर चयनकर्ताओं के बारे में क्या ख्याल है? टीम की विजय के क्षणों में चयनकर्ताओं को न तो कोई याद करता है और न ही कोई इतनी शाबाशी देने की जहमत उठाता है कि वाह साहब! आपने क्या टीम चुनी थी? बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जब टीम की गलतियों की सजा क्रिकेट कंट्रौल बोर्ड (बीसीसीआई) नें चयनकर्ताओं को दी। कप्तान अपनी जगह पर बरकरार रहा और चयनकर्ता बाहर कर दिये गये। कुछ और काम ऐसे होते हैं, जिनमें कोई तुक नहीं होती। मसलन, चयन समिति में जल्दी-जल्दी परिवर्तन। इससे टीम के चुनाव में फर्क पड़ता है। कुछ समय बाद ही चयनकर्ता खिलाड़ियों की अच्छाइयों से परिचित हो पाता है, जिससे चयन का काम आसान हो जाता है। क्षेत्रीय चयन की अवधारणा ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि चयनकर्ता खिलाड़ियों को उनके क्षेत्र में खेलते हुए देखते रहते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें सैकड़ों खिलाड़ी हैं। यह प्रक्रिया ज्यादा दिन नहीं चल सकती। चयनकर्ताओं के लिये व्यावहारिक रूप से बिलकुल असंभव है कि वे पूरे देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जांचते रहें। **—मनमोहन सूद**

मनमोहन सूद टेस्ट खिलाड़ी और दिल्ली के कप्तान रह चुके हैं। बाद में वह राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य भी रहे। वर्तमान में दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसियेशन के मानद खास सचिव हैं।

विकेटकीपर की भूमिका निर्णायक होती है

एक दशक से भी ज्यादा सैयद किरमानी का नाम भारतीय क्रिकेट पटल पर एक विकेटकीपर की हैसियत से छाया रहा। वह न केवल भारत के, बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में से एक माने जाते थे। १९८३ की विश्वकप विजेता टीम के वह महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने पांच कैच लेने के कीर्तिमान की बराबरी भी की। यहां वह यानी 'किरी' एक दिवसीय क्रिकेट में विकेट कीपर के महत्व और परेशानियों का विश्लेषण कर रहे है।

एक दिवसीय क्रिकेट हो या पांच दिवसीय, विकेट कीपर की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण और निर्णायक मानी जाती है। उसकी एक भूल से टीम जीते हुए मैच से हाथ धो सकती है और एक शानदार प्रयास से हारती हुई टीम विजयी हो सकती है। विकेट के पीछे रन रोकने में तो उसे महारत हासिल होनी ही चाहिए। विकेट कीपर के साथ एक विडंबना और जुड़ी होती है। किसी खास प्रयास पर उसे उतनी शाबाशी नहीं मिलती जितनी एक गलती पर दर्शकों की आलोचना सुननी पड़ती है।

एक दिवसीय क्रिकेट में विकेट कीपर के लिए चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए, मगर दो मूल गुण जो होने चाहिए वे हैं—अनुभव और परिपक्वता। सहायता और मार्गदर्शन का एक महान स्रोत होता है, वह विशेषकर कप्तान और गेंदबाजों के लिए। कितु वह यह मार्गदर्शन तभी प्रस्तुत कर सकता है जब उसका घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शिरकत का पर्याप्त अनुभव हो। एक अच्छे विकेट कीपर में अप्रतिम निर्णय, दक्षता और पूर्वानुमान की सही समझ आवश्यक है। उसे अपने गेंदबाजों की पूर्ण जानकारी तथा बल्लेबाजों की कमजोरियों और खूबियों का पता होना चाहिए। इससे उसे कप्तान अथवा गेंदबाजों का मार्गदर्शन करने और सलाह देने में सहायता मिलती है। संक्षेप में, उसे खेल का बेहतरीन जज (निर्णायक) होना चाहिए। अपने को चुस्त दुरुस्त रखने वाले विकेट कीपर को कसरत, अभ्यास और प्रशिक्षण में अत्यधिक नियमित होना चाहिए। जिस प्रकार तीन महान 'डब्ल्यूस' (वीक्स-वारेल-वालकाट) थे। सफलता पाने के लिए अनुशासन, दृढ़ निश्चय और समर्पण अत्यावश्यक है। विकेट कीपर के लिए कसरत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन के १०० ओवरों में लगभग साढ़े ७ घंटे की अवधि में उसे अनुमानतः ४ हजार बार गति में रहना पड़ता है। रोज बुनियादी कसरतों के साथ उसे तरह-तरह से कैचों को लेना चाहिए। इससे उसे पूर्वानुमान और फौरी प्रतिक्रियाओं में मदद मिलती है। एक दिवसीय और पांच दिवसीय क्रिकेट में काफी फर्क होता है।

जो कौशल आप पांच दिनों में दिखाते हैं उसे सामूहिक रूप में एक दिन में पेश करना पड़ता है। इसका मतलब है चार गुना अधिक मेहनत और एकाग्रता। खिलाड़ी को एक दिवसीय क्रिकेट निचोड़ डालता है। मैदान पर एक चूक या एक जोरदार व्यक्तिगत प्रदर्शन खेल की रंगत बदल देता है, जबकि टेस्ट क्रिकेट के पांच दिवसीय खेल में स्थिति सुधारने और मैदान में दुबारा आने का समय आपके पास होता है।

एक दिवसीय क्रिकेट में एक साधारण टीम सर्वोत्तम टीम को पछाड़ सकती है। भारत की मिसाल लें। इग्लैंड में संपन्न १९८३ के प्रुडेंशियल विश्व कप में भारत ने आश्चर्यजनक ढंग से प्रुडेंशियल कप जीता। भारत ने संपूर्ण विश्व के सम्मुख मिसाल पेश की कि क्रिकेट के महान खेल में पहले से निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह खासकर एक दिवसीय खेल में लागू होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर या विकेट कीपर में से किसी की एक भूल चूक बड़ी महंगी साबित हुई है। यह कहावत पूरी तरह लागू होती है 'कैचेज विन द मैचेज'। एक पल की गफलत पासा पलट सकती है। इसलिए पूरी सजगता, तन्मयता पहली शर्त है इसकी।

मैं उन लोगों का भ्रम दूर करना चाहता हूं, जो कहते हैं, भारत ने विश्व कप संयोग से जीत लिया। संयोग एक बार हो सकता है तीन बार नहीं। छह माह की अवधि में भारत ने शक्तिशाली वेस्टइंडीज टीम को तीन बार पराजित किया—एक बार उनके गृह नगर में और दो बार विश्व कप के दौरान। स्मरण रहे कि भारत ने प्रतियोगिता में उपेक्षित टीम के रूप में प्रवेश किया था, क्योंकि अतीत में उसका कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था।

भारत ने टूर्नामेंट में जो पहला मैच खेला और जीता वह वेस्टइंडीज (जो उस समय का चैंपियन था) के विरुद्ध था। उससे हम सबको बड़ी नैतिक शक्ति मिली और उसके बाद हमने

एक दिवसीय क्रिकेट में विकेट कीपर को हर क्षण चौकस रहना पड़ता है

क्या यह क्षण फिर दोहराये जायेंगे ? : सिर पर वर्ल्डकप (१९८३) रखे किरमानी

कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय टीम की हर चाल उसके पक्ष में सिद्ध हुई। यद्यपि हमारे गेंदबाज साधारण किस्म के थे किंतु हमारे क्षेत्ररक्षकों (फील्डर्स) ने कैच या रन आउट का कोई मौका नहीं छोड़ा। विपक्ष को पूरा भरोसा था कि भारत मुंह की खायेगा किंतु जब उन्हें हमारी शक्ति का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी और हम विजयी होकर उभरे।

भारतीय खिलाड़ियों के कुछ यादगार कारनामे हैं। कपिल की १७५ की सर्वोच्च व्यक्तिगत रन संख्या और ९वीं विकेट की रिकार्ड साझेदारी में २०० से अधिक रनों में मेरा ३८ रन बनाकर अविजित (नाट आउट) रहना समूचे टूर्नामेंट की विशेषता थी। यह मैच जिबाब्वे के विरुद्ध खेला गया था। यह मैच पूरी तरह कपिल का था किंतु मात्र उसके प्रदर्शन से हम फाइनल में न पहुंचते। रोजर बिन्नी ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिये और मैंने एक दिवसीय क्रिकेट में पांच को धराशायी करके विश्व रिकार्ड की बराबरी की तथा टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर का पुरस्कार प्राप्त किया। यह सब १९८३ के प्रुडेंशियल विश्व कप की सुखद स्मृतियां हैं जो आजीवन मेरे साथ रहेंगी।

किरमानी की पहली पसंद: सदानंद विश्वनाथ

वेस्टइंडीज और भारत के मध्य नाटकीय फाइनल का मंच सज चुका था। यह एक अविश्वसनीय रोमांचक कथा के समान है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और ६० ओवर में मात्र १८३ रन बनाये जो शक्तिशाली वेस्टइंडीज के सामने बहुत आसान था। लेकिन बलविंदर संधू का पहला ओवर उसके लिये झटका साबित हुआ। सलामी बल्लेबाज गार्डन ग्रीनिज आउट हो गया। फिर आया 'किंग' रिचर्ड्स। उसने जिस ढंग से हमारे गेंदबाजों की धुनाई की और आनन-फानन में ३० रन बनाये, उससे लगा वेस्टइंडीज कुछ ही घंटो में अपने ७-८ विकेट शेष रख हमें पीट लेंगे। हमारे मात्र १८३ रन से उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था, किंतु वेस्टइंडीज को सबसे बड़ा आघात रिचर्ड्स की विदाई से लगा। कपिल देव ने लगभग २५ कदम दौड़कर लाजवाब ढंग से मिड विकेट पर कैच लेकर खेल का रुख ही बदल दिया। वेस्टइंडीज पर दबाव बढ़ने लगा। अंतिम विजय में तीन कैचों के कमाल ने पूर्ण योगदान किया जिसमें गावस्कर द्वारा स्लिप्स पर दो और मेरा एक कैच शामिल था। इस प्रकार एक सपना सच हो गया।

अंतिम विकेट गिरने के पूर्व तक मुझे अपनी जीत का भरोसा नहीं था क्योंकि क्रिकेट में असंभव कुछ भी नहीं। यह समूची टीम की शानदार कोशिश या टीम भावना की वास्तविक अभिव्यक्ति थी। हरेक गेंदबाज विकेट लेने को आतुर और कटिबद्ध था, क्षेत्ररक्षा पूर्णतया चुस्त और चौकस थी। इस प्रकार हमने क्रिकेट में एकजुटता और प्रयास की सर्वोच्च मिसाल पेश की। दरअसल भारतीय क्रिकेट के लिए क्रिकेट के मक्का-लार्ड्स में वह एक महान दिन था।

—सैयद किरमानी

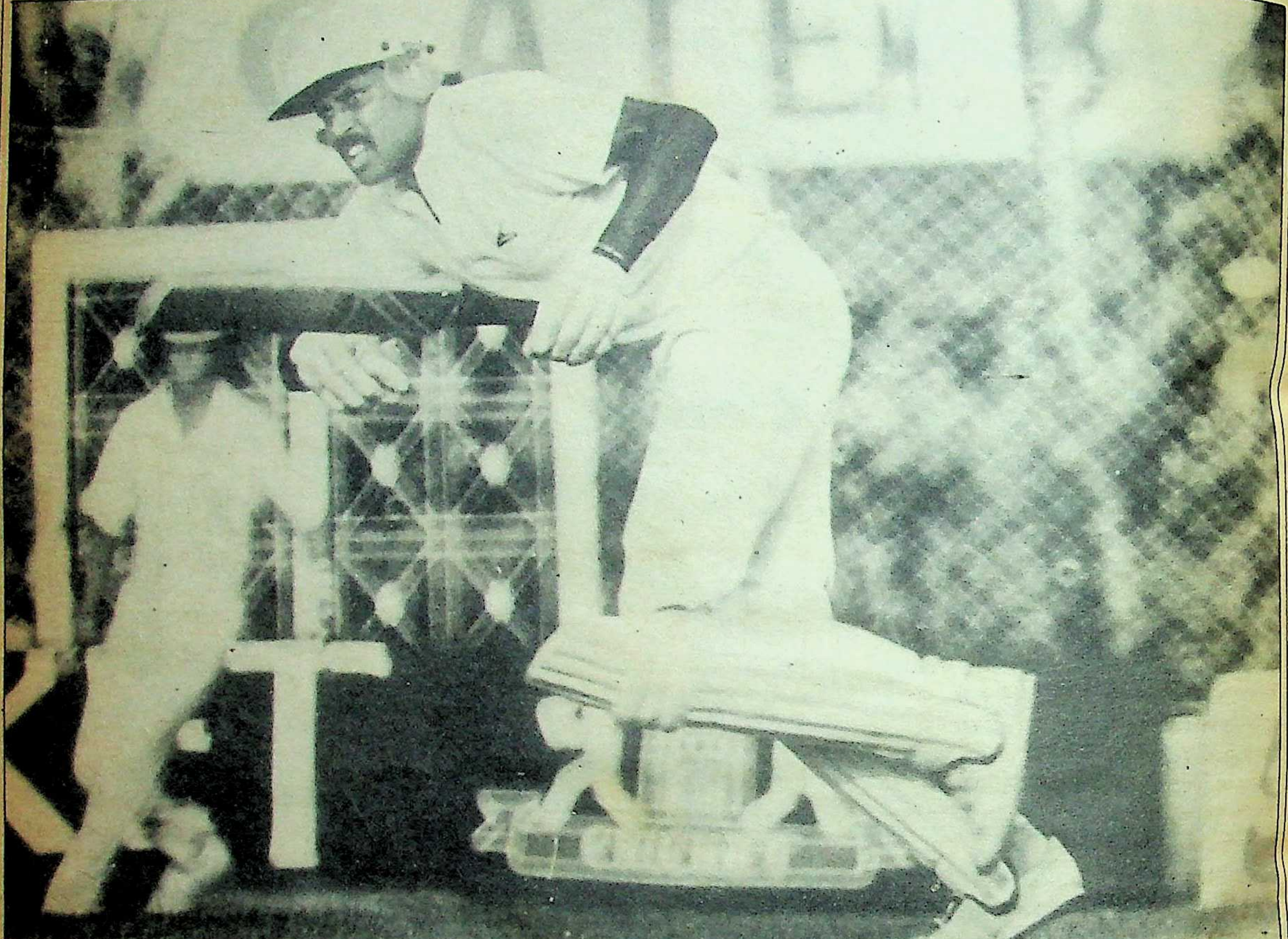

फिर याद आयेगी कपिल की मैराथन पारी

एक पिद्दी सी टीम के खिलाफ भारतीय टीम के घटिया प्रदर्शन को कोसते हुए ज्यादातर क्रिकेट प्रेमियों ने अपने रेडियो सेट बंद करके किनारे रख दिये। पहले दो मैचों में शानदार विजय हासिल करने के कारण उन्होंने बहुत उम्मीदें बांध रखी थीं। हालांकि तीसरे मैच में आस्ट्रेलिया से १६२ रन की करारी मात भी मिली थी, मगर विश्व विजेता वेस्टइंडीज को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमी जिबाब्वे जैसी नौसिखिया टीम से अपनी टीम को हारते देखने के लिए तैयार नहीं थे। मगर अनिश्चितताओं से भरे इस खेल के तब वे और कायल हो गये जब बाजी उलटती देख उन्हें अपने रेडियो दोबारा खोलने पड़े।

जिबाब्वे से भिड़ने के पहले भारत ने दो मैच जीते थे और दो हारे थे। सेमीफाइनल में पहुंचने की दृष्टि से भारत के लिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिवसीय मैचों में यह कहना खतरे से खाली नहीं होता कि फलां टीम कमजोर है, मगर अनुभव के लिहाज से जिबाब्वे जीरो थी, इसलिए भारत की जीत की उम्मीद सभी को थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि पहले हुए मैच में भारत ने जिबाब्वे को पांच विकेट से रौंदा था। इन तमाम भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए जिबाब्वे ने ऐसी शुरुआत की कि सभी दंग रह गये।

टास जीतने के बाद कप्तान क्लाइव राइस ने भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। पिछले दो मैचों में बाहर रहे सुनील गावस्कर ने श्रीकांत के साथ पारी की शुरुआत की। लेकिन शुरू से ही भारत को झटके लगने शुरू हो गये। गावस्कर और श्रीकांत बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गये। टिकाऊ बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ पांच रन जोड़कर चलते बने। तेज-तर्रार संदीप पाटिल केवल खाता ही (१ रन) खोल पाये। स्कोर हो गया नौ रन पर चार विकेट। यशपाल ने संभलकर खेलना शुरु किया, मगर नौ रन जोड़ते-जोड़ते उन्होंने भी क्रीज छोड़ दी। स्कोर हो गया १७ रन पर पांच विकेट। और यही वह समय था जब क्रिकेट-प्रेमियों ने नाउम्मीद होकर कमेंट्री सुननी बंद कर दी। यह गैर वाजिब नहीं था, क्योंकि इस स्थिति में भला भारत की जीत की उम्मीद

कौन कर सकता था? सोचा तो यह जाने लगा था कि आज भारत विश्व कप का न्यूनतम स्कोर (४५ रन) बनायेगा।

मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है। इसमें कब कौन क्या कर गुजरे कहना मुश्किल है और शायद यही क्रिकेट की खूबी भी। सत्रह रन पर पांच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद कपिल देव मैदान में उतरे। अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने आराम से खेलना शुरू किया। दूसरे छोर पर खड़े रोजर बिन्नी ने भी अपने कप्तान का साथ निभाना शुरू किया। मगर खतरा अभी टला नहीं था। छठे विकेट के लिए अभी ६० रन ही जुड़े थे कि बिन्नी (२२ रन) के डंडे बिखर गये। रवि शास्त्री भी एक रन का ही इजाफा कर पाये और स्कोर हो गया—सात विकेट पर ७८ रन। ऐसा लगने लगा कि भारत १०० रन की सीमा पार नहीं कर पायेगा, मगर पहले दर्जे में क्रिकेट में बल्लेबाज के रूप में लगभग असफल खिलाड़ी मदनलाल ने एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू किया। लंच के समय जब अंपायरों ने गिल्लियां अपने जेबों के हवाले कीं, तो स्कोर था सात विकेट पर १०६ रन। यानी मंजिल अभी बहुत दूर थी। हां, इन विषम परिस्थितियों में भी कपिल ने अपना आधा सैकड़ा पूरा कर लिया था।

लंच के बाद आठवें विकेट की साझेदारी में ६९ रन जुड़े और मदनलाल की पारी का अंत हुआ। मदन लाल ने बनाये तो केवल १७ रन, मगर अच्छे स्कोर के लिए आधार शिला रखने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। दूसरे छोर पर खड़े कपिल अपने साथियों को आते-जाते देख रहे थे, मगर एक लंबी पारी खेलने का निश्चय भी उनके चेहरे से झलक रहा था। किरमानी भी मदनलाल की भांति रन बनाने के बजाय कप्तान का साथ देने आये। ४९वें ओवर में कपिल ने एक दिवसीय मैचों में अपना पहला शतक बनाया। लेकिन क्या यह शतक केवल कपिल का था? इस एक शतक ने भारतीय टीम में जो आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया उसने बाद में एक इतिहास बना डाला।

शतक पूरा करने के बाद कपिल देव खुलकर खेलने लगे। उन्होंने करने के एक ओवर में १८ रन भी ठोंके। इसी बीच उन्हें एक आसान-सा जीवनदान भी मिला, लेकिन अविचल कपिल बढ़ते रहे। चौकों-छक्कों की बरसात शुरू हो गयी। अंततः ६०वें ओवर की समाप्ति पर भारत ने अच्छा-खासा स्कोर खड़ा कर लिया—आठ विकेट पर २६६ रन। इसमें कपिल देव के १७५ रन शामिल थे, जो छह छक्कों और सोलह चौकों की सहायता से बने थे। विश्व कप मैचों में यह सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। इसके पहले न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर ने १७१ रन बनाये थे। कपिल के रिकार्ड के अलावा एक और नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। कपिल और किरमानी ने मिलकर नवें विकेट की रिकार्ड साझेदारी में १२६ रन जोड़े। हालांकि किरमानी का योगदान इसमें केवल २४ रन का रहा, मगर कपिल का साथ देकर ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभायी थी।

आगामी रिलायंस कप में भी ऐसे क्षण बार-बार आयेंगे जब टीम की हालत खस्ता हो रही होगी। तब रह-रहकर याद आयेगी, 'कपिल की वह मैराथन पारी'।

—मुकेश जैन

'लिटिल मास्टर' का एक और रिकार्ड

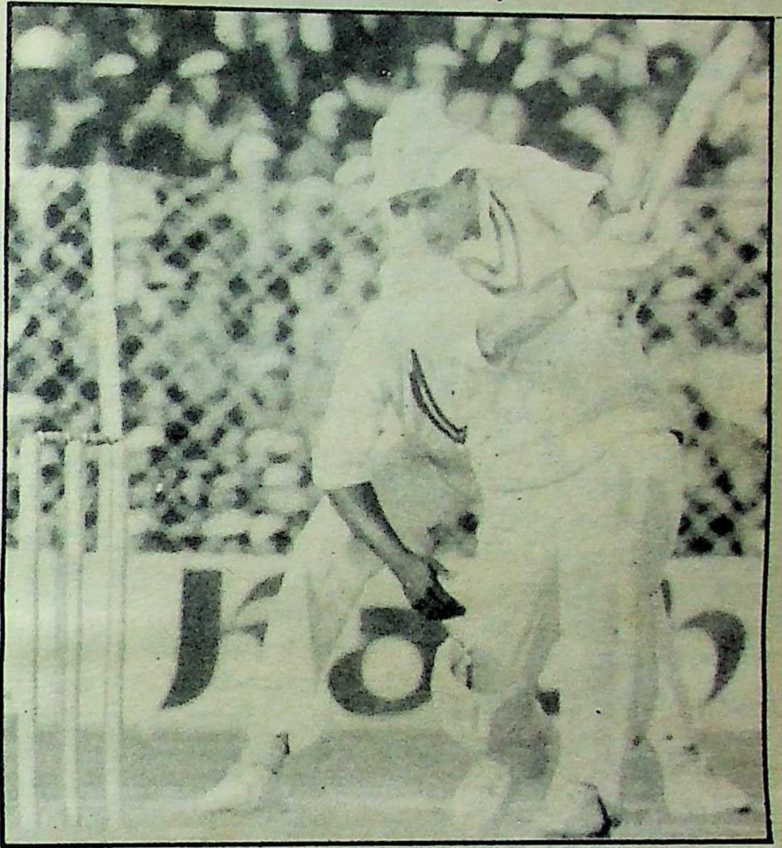

रिकार्ड किंग

दुनिया के सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम ढेरों रिकार्ड हैं, इसीलिए उन्हें 'रिकार्ड मेकर' भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा अर्ध शतक, सबसे ज्यादा टेस्ट और जाने कितने ही ऐसे रिकार्ड हैं, जिन्हें तोड़ने की तमन्ना हर युवा खिलाड़ी के दिल में होगी। लेकिन उनके हिस्से में एक रिकार्ड ऐसा भी है, जो किसी भी बल्लेबाज की हसरत नहीं हो सकता। खुद सनी भी अपने उस रिकार्ड को याद करने से कतराते होंगे।

बात पहले विश्वकप के उद्घाटन मैच की है। ७ जून, १९७५ को हुए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ६० ओवर में चार विकेट पर ३३४ रन का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रखा। इस स्कोर में कप्तान डी० एनिस के शानदार १३७ रन शामिल हैं, जो विश्व कप का पहला शतक भी है। जब भारत की बारी आयी, तो उसने टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में खेलना शुरू किया। एक दिवसीय मैचों का जरा भी अनुभव न होने के कारण भारतीय बल्लेबाज पूरे ६० ओवर तक क्रीज पर तो टिके रहे मगर रन बने केवल १३२ (३ विकेट पर) ही। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम एक दिवसीय मैचों की तकनीक से पूरी तरह नावाकिफ थी, मगर सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एक सिरा जो पकड़ा, तो अंत तक छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि पूरे ६० ओवर तक विकेट पर खड़े रहने के बाद रन मशीन के बल्ले से केवल ३६ (नाबाद) रन ही निकले। इस बीच उनके बाद आये गुंडप्पा विश्वनाथ ३७ रन बनाकर पवेलियन भी लौट गये। भारतीय टीम के अन्य बल्लेबाज और क्रिकेट प्रेमी मना रहे थे कि गावस्कर आउट हो जायें। खुद कप्तान वेंकट राघवन बार-बार पहलू बदल रहे थे कि शायद अगली गेंद से गावस्कर के विकेट का काम तमाम हो जाये, जिससे कोई दूसरा बल्लेबाज स्थिति को सुधारने के लिए भेजा जा सके। मगर मजाल था कि गावस्कर आउट हो जायें। दरअसल, इंग्लैंड के खिलाड़ी भी समझ रहे थे कि गावस्कर का जमे रहना उनके फायदे में है और वे उन्हें आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि गावस्कर भी खुद जमे रहने के इच्छुक थे। वह बार-बार विकेट से हट जाते कि अब बोल्ड हो जायें और लौटे पवेलियन, मगर गेंद उनसे भी ज्यादा चालाक साबित हो रही थी।

गावस्कर ने अपनी पुस्तक 'सनी डेज' में लिखा है, "वह मेरी सबसे घटिया पारी थी और मैं उसे याद नहीं करना चाहता।"

—मुकेश जैन

विशेषज्ञों की नजर में

रिलायंस कप ने न सिर्फ आम क्रिकेट प्रेमियों में असीमित दिलचस्पी जगा दी है, बल्कि क्रिकेट के किसी भी पक्ष से जुड़े लोग चाहे वे खिलाड़ी, अधिकारी या प्रशिक्षक या फिर अंपायर हों, सभी इसके रंग-में-रंग गये हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से 'माया' ने रिलायंस कप के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। आमतौर पर सभी इस बात पर सहमत थे कि स्वरूप और लोकप्रियता के आधार पर रिलायंस कप पिछले विश्वकपों से बाजी मार ले जायेगा, पर जब इसके संभावित नतीजों के बारे में अंदाजा लगाने की बात आयी, तो उनकी राय में जमीन आसमान का फर्क रहा।

संभावित विजेता कौन होगा? भारत की जीत की कितनी उम्मीद है? कौन से खिलाड़ी चमत्कार कर सकते हैं? इस बारे में विशेषज्ञों की राय इस प्रकार रही—

एम०एल० जयसिम्हा

(भूतपूर्व टेस्ट खिलाड़ी)

इतने सारे तोप खिलाड़ी आ रहे हैं। हमने बहुत सी उम्मीदें पाल ली हैं लिहाजा मैं तो यही कामना करता हूं कि रिलायंस कप गड़बड़ा न जाये। इस प्रतियोगिता के बाद सीमित ओवर की क्रिकेट पर और ज्यादा जोर दिया जा सकता है। जो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि एक दिन का क्रिकेट नियमित और पारंपरिक क्रिकेट की कीमत पर विकसित किया जा रहा है। एक दिन के क्रिकेट का बड़ा आकर्षण है उसमें मनोरंजन कर सकने का माद्दा है, पर टेस्टों की अपनी अलग चमक है। यही असली चीज है।

पहले मैं वेस्टइंडीज को संभावित विजेता मानता था, पर अब जबकि उसके कई खिलाड़ी नहीं आ रहे, पाकिस्तान चोटी पर पहुंच सकता है। भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो भी उसे नजरंदाज करना गलती होगी। हमारी टीम एक या दो चमत्कार कर सकने के काबिल तो है ही। खिलाड़ियों के बारे में कोई अंदाजा लगाना मैं पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी चीजों की भविष्यवाणी कर पाना असंभव है। लेकिन यह तय है कि प्रतियोगिता अपने नायक खुद पैदा करेगी।

बिशन सिंह बेदी

(भूतपूर्व भारतीय कप्तान)

लोगों ने एशियाड में जितनी ज्यादा दिलचस्पी ली थी, उतनी दिलचस्पी वे विश्व कप में तो लेते हुए मुझे दिखायी नहीं दे रहे। पर विश्व कप मीडिया के लिए कड़ी चुनौती होगा। एक राष्ट्र के रूप में बतौर आयोजक हमारी काबिलियत फिर कसौटी पर है।

मेरी राय में पाकिस्तान विश्व कप जीतने का प्रमुख दावेदार है। दूसरा नंबर इंग्लैंड का है। इंग्लैंड की टीम साधारण जरूर है, पर यह मत भूलिए कि उसने शारजाह में तब जीत पायी थी, जब उसके आधे अच्छे खिलाड़ी नदारद थे। भारत का 'ड्रा' आसान है, पर मुझे उसके लिए कोई उम्मीद नहीं दिखती। मैं किसी खास खिलाड़ी को लेकर उत्सुक नहीं हूं। मुझे अच्छा क्रिकेट देखकर ही खुशी होगी, चाहे अच्छा क्रिकेट कोई भी क्यों न खेले। खेल हमेशा खिलाड़ियों से ज्यादा महान होता है।

कैलाश गट्टानी

(राजस्थान और मध्य क्षेत्र के भूतपूर्व कप्तान)

रिलायंस कप के प्रति मेरा उत्साह कुछ हद तक कमजोर पड़ गया है। तेज गेंदबाज मार्शल और गारनर, आलराउंडर हैडली और बाथम व गावर और ग्रीनिज जैसे बल्लेबाज नदारद हैं। आलराउंडरों की कमी खासतौर से खलेगी, क्योंकि एक दिन के मैच ही उनकी प्रतिभा के सर्वथा उपयुक्त होते हैं।

मेरा मानना है कि विश्व कप से प्रेरणा लेकर बहुत से युवा क्रिकेट खेलने लगेंगे। रिलायंस कप के प्रति तो जबर्दस्त उत्साह रहेगा ही।

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें मजबूत हैं, तो भी आप भारतीय टीम को अनदेखा नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि कमजोर गेंदबाजी की वजह से वह अपंग है। खिलाड़ियों में मैं चाहूंगा कि कपिल एक कप्तान और एक गेंदबाज दोनों रूपों में अच्छा प्रदर्शन करें। उनके बारे में काफी कुछ कहा गया है और उसे गलत साबित करने का सबसे बढ़िया तरीका मैदान में अच्छा प्रदर्शन करना है।

मंसूर अली खां पटौदी

(भू०पू० भारतीय कप्तान और 'स्पोर्ट्सवर्ल्ड' के संपादक)

रिलायंस कप में लोगों की दिलचस्पी इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कैसा प्रदर्शन करता है। अगर हम ठीक प्रदर्शन कर पाते हैं, तो क्रिकेट समर्थक बहुत ज्यादा रोमांचित हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि विश्वकप की वजह से ज्यादा लोग क्रिकेट खेलने लगेंगे। यह खेल तो वैसे भी हर गली-नुक्कड़ में खेला जाता है, पर जब विश्व कप चल रहा होगा, तो इसमें हर एक की दिलचस्पी होगी।

आज के हालात में मैं विश्व विजेता के रूप में पाकिस्तान का नाम लूंगा। एक तूफान मचा रखा है इस टीम ने। इंग्लैंड तो कतई नहीं जीत सकता। उसकी टीम काफी मामूली है। भारत का 'ड्रा' अच्छा है, पर भारतीय खिलाड़ियों की फार्म उतनी उत्साहवर्द्धक नहीं है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि विश्व कप में वेंगसरकर, क्रो और मियांदाद अच्छा असर छोड़ेंगे।

आकाश लाल

(दिल्ली, पजाब और उत्तरी क्षेत्र के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान और कमेंटेटर)

मुझे नहीं लगता कि विश्व कप का कोई ज्यादा असर पड़ेगा। हम कुछ समय इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद सब कुछ भुला दिया जायेगा। जब हम कोई टेस्ट शृंखला खेलते हैं तब भी पूरे देश में यही होता है।

पाकिस्तान विश्वकप जीत सकता है। उसका मनोबल सचमुच काफी ऊंचा है। मुझे भारत की कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर हम श्रीलंका से भी नीचे रहें। वेस्टइंडीज के रिचर्ड्स, ग्रीनिज, हेंस और रिचर्डसन सचमुच मैच के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। गेंदबाजी में मेरी निगाह रहेगी वसीम अकरम पर। पिछले साल जब वह भारत आया था, तो उसने मुझे काफी प्रभावित किया था।

सुनील वालसन

(१९८३ में विश्वकप जीतने वाली टीम के सदस्य)

विश्वकप जीतने की अनुभूति बखान कर पाना मुश्किल काम है। अनुभव रोमांचपूर्ण था और अगर हम खिताब बरकरार रख पाते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। भारतीय टीम का मौजूदा प्रदर्शन कैसा भी रहा हो, मेरा मानना है कि हमें भारत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान की टीम अच्छी है। लेकिन एक दिन की क्रिकेट में उसने अभी तक शायद ही कोई बड़ी सफलता पायी है। कुछ लोग लगता है भारत को भाव नहीं दे रहे। बहरहाल, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं।

अशोक मल्होत्रा

(टेस्ट खिलाड़ी)

रिलायंस कप एक बहुत बड़ी घटना है और मैं इसे टेलीविजन पर देखूंगा। विश्वकप पहले से ही दिलचस्पी पैदा कर रहा है। मैं उन अभिभावकों को देखता हूं जो अपने उन बच्चों को भी नेट्स पर ला रहे हैं, जिनकी उम्र पांव पर चलने की भी नहीं हुई है। पहले की तुलना में ज्यादा नौजवान क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हैं।

मैं तो भारत की जीत पर शर्त बदूंगा। 'ड्रा' अच्छा है। हम लोग हमेशा दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते आये हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारी टीम काफी शानदार है। वैसे लोग ज्यादा उम्मीद न करें, तो तनाव ही कम होगा। मेरी राय में श्रीकांत और रिचर्डस सफल होंगे और गेंदबाजों में वाल्श, इमरान व कपिल।

स्वरूप किशन

(भूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर)

मुझे इस बात की चिंता है कि शायद एक दिन में सौ ओवर न फेंके जा सकें। और अगर मैच दूसरे दिन जारी रहता है, तो एक दिन के मैचों की अवधारणा मात खा जायेगी। आपको ताजी शुरुआत करनी होगी और सारा रोमांच हवा हो चुका होगा, मैं नहीं सोचता कि विश्व कप की वजह से और ज्याद लोग क्रिकेट खेलने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे गैर क्रिकेटर प्रेरणा लेंगे।

मैं तो यही कामना करता हूं कि भारत जीते पर इस समय कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है, खासतौर से जब टीमों के गठन के बारे में कोई जानकारी न हो। वेस्टइंडीज की टीम सबसे बेहतर लगती है, पर असली बात यह है कि खेल वाले दिन कौन बेहतर खेलता है। मैं न्यूजीलैण्ड और जिबाब्वे के खिलाड़ियों को खेलते देखना ज्यादा पसंद करूंगा। उनमें मेरी दिलचस्पी की खास वजह यह है कि मैंने उन्हें कभी खेलते नहीं देखा है।

दलजीत सिंह

(सेना और बिहार के भूतपूर्व विकेट कीपर व बल्लेबाज)

उदयपुर के नाटक के बाद मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूं कि विश्व कप कमजोर आयोजन का शिकार न बने। सब कुछ व्यवस्थित करने और तमाम बातों पर गौर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी छोटे केन्द्रों की है। विश्व कप की वजह से कई किशोरों को क्रिकेट के लिए प्रेरणा मिलेगी। खेल को भी फायदा होगा और उनको भी जो खिलाड़ियों को भी टेलीविजन पर टमाटर की चटनी बेचते दिखायी देते हैं। एक दिन के क्रिकेट और पांच दिन के क्रिकेट में अपने यहां और बाहर के हाल के प्रदर्शन को देखा जाये, तो पाकिस्तान की विश्व कप जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। वेस्टइंडीज का दूसरा नंबर है। भारत का 'ड्रा' आसान है, लेकिन गेंदबाजी काफी कमजोर है। अगर हम सही क्षेत्ररक्षण कर पायें और बल्लेबाज चुनौती कबूल कर पायें, तो हम भी जीत सकते हैं। अकरम और डी फ्रेटास ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो मैच के नतीजे पर असर डाल सकते हैं।

चेतन चौहान

(भूतपूर्व टेस्ट खिलाड़ी और फिलहाल राष्ट्रीय चयनकर्ता)

सभी लोगों की तरह मैं भी विश्वकप का इंतजार कर रहा हूं। क्रिकेट के शौकीनों को ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना भर था। विश्व कप का आयोजन हमें प्रतिष्ठा देगा। बाहर के लोगों को भारत के एक अलग रूप के दर्शन होंगे। उन लोगों की हमारे बारे में तमाम गलत धारणाएं बनी हुई हैं। भारत में भी विश्व कप से जो उत्सुकता पैदा होगी उससे क्रिकेट और दूसरे खेलों को भी फायदा होगा।

भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में से कोई भी यह प्रतियोगिता जीत सकता है। भारत को 'ड्रा' का फायदा है। धीमे विकेट का लाभ भी उसे है। देखने लायक प्रदर्शन श्रीकांत, वेंगसरकर; क्रो, रिचर्डस व ग्रीनिज का होगा।

आई०एस० बिन्द्रा

(भारत-पाक संयुक्त आयोजन समिति के संयोजक)

टेलीविजन कवरेज और ज्यादा दर्शकों के आधार पर रिलायंस कप एशियाड से भी ज्यादा बड़ा आयोजन होने जा रहा है। लाखों लोग इसे देखेंगे। विश्वकप से जो उत्सुकता पैदा होगी, उसका निश्चित रूप से लंबे समय तक असर पड़ेगा। विभिन्न टीमों की संभावनाओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यह एक व्यापक क्षेत्र है। लेकिन निश्चित रूप से बेहतर टीम ही विश्वकप जीतेगी।

अशोक गंडोत्रा

(भूतपूर्व टेस्ट खिलाड़ी)

मैं समझता हूं कि विश्वकप पूरे देश को रोमांचित कर देगा और यह निश्चित रूप से ऐसा बड़ा आयोजन होगा जिसमें सबकी दिलचस्पी होगी। यह तय है कि बहुत से युवकों को इससे क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिलेगी और एक दिन के क्रिकेट की लोकप्रियता और बढ़ेगी। मैं निजी तौर पर इस बात से काफी रोमांचित हूं कि विश्व की बेहतरीन टीमें भारत में जुट रही हैं।

बाकी सभी लोगों की तरह मैं भी महसूस करता हूं कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विश्वकप जीतने की ज्यादा अच्छी संभावना है। फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम अच्छा खेल नहीं दिखा पा रही, पर व्यक्तिगत तौर पर उसके खिलाड़ी महान हैं और अपनी कोशिशों से मैच का रुख बदल देने की उनमें पूरी काबिलियत है। सीमित गेंदबाजी की वजह से भारत विश्वकप जीतने का गंभीर दावेदार नहीं बन पायेगा, खासतौर से उस हालत में जबकि यह पता ही नहीं है कि हमारे विकेट हमारे अपने गेंदबाजों को मदद कर पायेंगे या नहीं। खिलाड़ियों में मुझे विव रिचर्डस से ही ज्यादा उम्मीद है।

अंशुमान गायकवाड़

(भूतपूर्व सलामी बल्लेबाज)

निश्चित रूप से यह एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। माहौल पहले से ही बन रहा है। एक दिन का क्रिकेट काफी लोकप्रिय है, यहां तक कि गृहणियों में भी। यह एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। धीरे-धीरे ज्यादा समय के मैचों की कीमत पर एक दिन का क्रिकेट विकसित होगा। टेस्टों की तुलना में अब एक दिन के क्रिकेट पर पहले से ही जोर दिया जा रहा है। बड़ी कंपनियों की स्पांसरशिप मिले और ज्यादा पैसा आया, तो रही-सही कसर भी पूरी हो जायेगी।

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के विश्व कप जीतने के आसार हैं। वेस्टइंडीज के इसलिए कि वह सर्वगुण संपन्न है और पाकिस्तान के इसलिए कि उसके खिलाड़ी जबर्दस्त फार्म में हैं। भारत को अपने ही विकेटों पर जूझना होगा, क्योंकि उसकी गेंदबाजी काफी कमजोर है। फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन करने के लायक हैं और फिर 'ड्रा' भी हमारे पक्ष में है। मेरी राय में बेहतर यही होगा कि आप सुनील गावस्कर को खेलते देखें। वही ऐसा अकेला खिलाड़ी है जो कुछ कर सकता है। मेरा मानना है कि वही प्रतियोगिता में छाया रहेगा।

गुरचरण सिंह

(राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान में क्रिकेट के प्रशिक्षक)

दूसरे लोगों की तरह मैं भी विश्व कप के लिए काफी रोमांचित हूं। कोई और खेल समारोह इसका मुकाबला नहीं कर पायेगा। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा फायदा नयी सुविधाएं जुटाने के रूप में होगा। अगर विश्वकप नहीं होता तो ये सुविधाएं मिलने में पचास साल और लग जाते। मिसाल के तौर पर उदयपुर के विकेट बेहतरीन भले ही न हों, युवा खिलाड़ियों के लिए तो वे उपलब्ध रहेंगे ही। आधुनिक स्टेडियम, बेहतर विकेट और खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा—यही तो विश्वकप के बड़े फायदे हैं।

मेरा मानना है कि भारत फाइनल में तो निश्चित रूप से पहुंचेगा। 'ड्रा' बढ़िया है। हमें अपने मैदानों पर खेलने का लाभ है। हमारी बल्लेबाजी काफी मजबूत है। कपिल का अनुभव भारत को विश्व विजय दिला सकता है। धीमें विकेटों की वजह से वेस्टइंडीज को नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम मजबूत है और वही हमारी मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगी।

—अमृत माथुर

टीमों का खेल रिकार्ड

एक नजर में १९८७ से १९८३

क्रमांक	टीम	आयोजन	खेले	जीते	हारे	अनिर्णीत	कुल अंक	जीत का औसत	विजेता
१-	वेस्टइंडीज	१८	१७	१५	२	१	६२	८६.११	दो बार
२-	इंग्लैंड	१६	१६	१२	४	-	४८	७५.००	-
३-	भारत	१४	१४	७	७	-	२८	५०.००	एक बार
४-	न्यूजीलैंड	१४	१४	७	७	-	२८	५०.००	-
५-	पाकिस्तान	१४	१४	६	८	-	२४	४२.८५	-
६-	आस्ट्रेलिया	१४	१४	६	८	-	२४	४२.८५	-
७-	श्रीलंका	१२	११	२	९	१	१०	२०.८३	-
८-	जिम्बाब्वे	६	६	१	५	-	४	१६.६६	-
९-	पूर्वी अफ्रीका	३	३	०	३	-	०	-	-
१०-	कनाडा	३	३	०	३	-	०	-	-

अनिर्णीत २ अंक, पराजित - शून्य अंक

सर्वोच्च भागीदारी

विकेट	भागीदारी	के मध्य में	देश	बनाम	स्थान	वर्ष
१	१८२	रिक मैकोस्कर/ए० टर्नर	आस्ट्रे०	श्रीलंका	ओवल	१९७५
२	१७६	डेनिस एमिस/कीथफ्लेचर	इंग्लैंड	भारत	लार्ड्स	१९७५
३	१९५	ग्रीनिज/गोम्स	वेस्टइंडीज	जिबाब्वे	वारसेस्टर	१९८३
४	१४९	सी०लायड/आर०कन्हाई	वेस्टइंडीज	आस्ट्रे०	लार्ड्स	१९७५
५	१३९	रिचर्ड्स/कोलन किंग	वेस्टइंडीज	इंग्लैंड	लार्ड्स	१९७९
६	१४४	इमरान खान/सी० महबूब	पाक	श्रीलंका	लीड्स	१९८३
७	७५	डी०फ्लेचर/आई० बुटचार्ट	जिबाब्वे	आस्ट्रे०	नार्टिघम	१९८३
८	६२	कपिलदेव/मदनलाल	भारत	जिबाब्वे	टर्नब्रिजवेल्स	१९८३
९	१२६	कपिल देव/किरमानी	भारत	जिम्बाब्वे	टर्नब्रिजवेल्स	१९८३
१०	७१	राबर्ट्स/जे० गारनर	वेस्टइंडीज	भारत	मानचेस्टर	१९८३

उच्चतम टीम प्रदर्शन

क्रमांक	टीम	रन	विकेट	बनाम	स्थान	वर्ष
१-	आस्ट्रेलिया	३२८	५	श्रीलंका	ओवल	१९७५
२-	कनाडा	१३९	९	पाक	लीड्स	१९७९
३-	पूर्वीअफ्रीका	१२८	८	न्यूजी०	बर्मिंघम	१९७५
४-	इंग्लैंड	३३४	४	भारत	लार्ड्स	१९७५
५-	भारत	२६६	८	जिंबाब्वे	टर्नब्रिज वेल्स	१९८३
६-	न्यूजीलैंड	३०९	५	ई०अ०	बर्मिंघम	१९७५
७-	पाकिस्तान	३३८	५	श्रीलंका	स्वांसी	१९८३
८-	श्रीलंका	२८८	९	पाक	स्वांसी	१९८३
९-	वेस्टइंडीज	२९३	६	पाक	ओवल	१९७९
१०-	जिंबाब्वे	२४०	१०	आस्ट्रे०	साउथैम्प्टन	१९८३

नोट: उपर्युक्त उच्चतम संख्या पूरे ६० ओवरों में प्राप्त की गयी है। जिंबाब्वे अपवाद है जो ५९.५ ओवर में आउट हो गया।

न्यूनतम टीम प्रदर्शन

क्रमांक टीम	स्कोर	विकेट	ओवर	बनाम	स्थान	वर्ष
१-आस्ट्रेलिया	१२९	१०	३८.२	भारत	चेम्सफोर्ड	१९८३
२-कनाडा	४५	१०	४०.३	इंग्लैंड	मानचेस्टर	१९७९
३-पूर्वी अफ्रीका	९४	१०	५२.३	इंग्लैंड	बर्मिंघम	१९७५
४-इंग्लैंड	९३	१०	३६.२	आस्ट्रे०	लीड्स	१९७५
५- भारत	१३२	३	६०.०	इंग्लैंड	लार्ड्स	१९७५
६- न्यूजीलैंड	१५८	१०	५२.२	वेस्टइंडीज	ओवल	१९७५
७-पाकिस्तान	१५१	१०	५६.०	इंग्लैंड	लीड्स	१९७९
८-श्रीलंका	८६	१०	३७.२	वेस्टइंडीज	मानचेस्टर	१९७५
९-वेस्टइंडीज	१४०	१०	५२.०	भारत	लार्ड्स	१९८३
१०जिंबाब्वे	१५५	१०	५१.४	भारत	लीशेस्टर	१९८३

नोट: 'आल आउट' या पूरे ६० ओवरों के संदर्भ में

सर्वोच्च विजय

विकेट से

अंतर	विजेता	पराजित	स्थान	वर्ष
१०	भारत	पूर्वी अफ्रीका	लीड्स	१९७५
१०	वेस्टइंडीज	जिंबाब्वे	बर्मिंघम	१९८३

रनों से

अंतर	विजेता	पराजित	स्थान	वर्ष
२०२	इंग्लैंड	भारत	लार्ड्स	१९७५
१९६	इंग्लैंड	पूर्वी अफ्रीका	बर्मिंघम	१९७५
१९२	पाक	श्रीलंका	नार्टिंघम	१९७५
१८१	न्यूजी०	पूर्वी अफ्रीका	बर्मिंघम	१९७५
१६२	आस्ट्रे०	भारत	नार्टिंघम	१९८३
११८	भारत	आस्ट्रे०	चेम्सफोर्ड	१९८३
१०६	इंग्लैंड	न्यूजी०	ओवल	१९८३
१०१	वेस्टइंडीज	आस्ट्रे०	लीड्स	१९८३

शतकधारी

क्रमांक	नाम	रन	देश	बनाम	स्थान	वर्ष
१-	कपिल देव	१७५	भारत	जिंबाब्वे	टनब्रिज	१९८३
२-	ग्लेन टर्नर	१७१	न्यूजीलैंड	ईस्टअफ्रीका	बर्मिंघम	१९७५
३-	विव रिचर्ड्स	१३८	वेस्टइंडीज	इंग्लैंड	लार्ड्स	१९७९
४-	डेनिस एमिस	१३७	इंग्लैंड	भारत	लार्ड्स	१९७५
५-	कीथ फ्लेचर	१३१	इंग्लैंड	न्यूजी०	नार्टिंघम	१९७५
६-	डेविड गोवर	१३०	इंग्लैंड	श्रीलंका	टाउंटन	१९८३
७-	विव रिचर्ड्स	११९	वेस्टइंडीज	भारत	ओवल	१९८३
८-	ग्लेन टर्नर	११४	न्यूजीलैंड	भारत	मानचेस्टर	१९७५
९-	ट्रेवर ,चैपल	११०	आस्ट्रे०	भारत	नार्टिंघम	१९८३
१०-	गोर्डन ग्रीनिज	१०६	वेस्टइंडीज	भारत	बर्मिंघम	१९७९
११-	"	१०५	"	जिंबाब्वे	वोसैस्टर	१९८३
१२-	जहीर अब्बास	१०३	पाक	न्यूजी०	नार्टिंघम	१९८३
१३-	इमरान खान	१०२	"	श्रीलंका	लीड्स	१९८३
१४-	क्लाइव लायड	१०२	वेस्टइंडीज	आस्ट्रे०	लार्ड्स	१९७५
१५-	एलन लैंब	१०२	इंग्लैंड	न्यूजी०	ओवल	१९८३
१६-	एलन टर्नर	१०१	आस्ट्रे०	श्रीलंका	ओवल	१९७५

कम अंतर से जीत

३ या कम विकेट से

अंतर	विजेता	पराजित	स्थान	वर्ष
१	वेस्टइंडीज	पाकिस्तान	बर्मिंघम	१९७५
२	न्यूजीलैंड	इंग्लैंड	"	१९८३
३	श्रीलंका	न्यूजीलैंड	डर्बी	१९८३

२० या कम रन से

अंतर	विजेता	पराजित	स्थान	वर्ष
०९	इंग्लैंड	न्यूजीलैंड	मानचेस्टर	१९७९
११	पाक	श्रीलंका	लीड्स	१९८३
११	पाक	न्यूजी०	नार्टिंघम	१९८३
१३	जिंबाब्वे	आस्ट्रे०	नार्टिंघम	१९८३
१४	इंग्लैंड	पाक	लीड्स	१९७९
१७	वेस्टइंडीज	आस्ट्रे०	लार्ड्स	१९७५

श्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े

विकेट	रन	गेंदबाज	देश	खिलाफ	स्थान	वर्ष
६	१४	ग्रे गिलमोर	आस्ट्रे०	इंग्लैंड	लीड्स	१९७५
२	२७	सी०सी०हेनरी	कैनेडा	आस्ट्रे०	बर्मिंघम	१९७९
३	६३	जुल्फिकारअली	ईस्ट अफ्रीका	इंग्लैंड	बर्मिंघम	१९७५
५	३९	विक० मार्क्स	इंग्लैंड	श्रीलंका	टाउनटन	१९८३
५	४३	कपिल देव	भारत	आस्ट्रे०	नार्टिंघम	१९८३
५	२५	रिचर्ड हैडली	न्यूजीलैंड	श्रीलंका	विस्टाल्स	१९८३
५	४४	अब्दुल कादिर	पाक	श्रीलंका	लीड्स	१९८३
५	३२	असांत डिमेल	श्रीलंका	न्यूजी०	डर्बी	१९८३
७	५१	विंस्टन डेविस	वेस्टइंडीज	आस्ट्रे०	लीड्स	१९८३
४	४२	डी फ्लेचर	जिम्बाब्वे	आस्ट्रे०	नार्टिंघम	१९८३

दर्शकों का व्यवहार खेल को खेल बना सकता है

किसी भी मनोरंजन में तीन पहलू अवश्य होते हैं। अभिनेता जो मनोरंजन प्रदान करता है, दर्शक जो इस मनोरंजन को संभव बनाते हैं और प्रबंधक जो इसकी व्यवस्था करते हैं। क्रिकेट भी मूल रूप से एक मनोरंजन है और खिलाड़ी इसके अभिनेता हैं। पर यह बात सच है कि जितने अधिक दर्शक होते है उतना ही मनोरंजन बढ़ जाता है। यद्यपि क्रिकेट का खेल विश्व के कुछ गिने-चुने देशों में ही खेला जाता है, फिर भी इस खेल का जो आकर्षण है वह अपने में एक कहानी है और वर्षों से उसका आनंद लेने के लिए हजारों की तादाद में दर्शक क्रिकेट मैदानों पर दिखायी देते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान यहां तक कि महिलायें आज क्रिकेट मैचों का बराबर हाल लेते रहते हैं और अच्छे खिलाड़ियो के नाम तथा उनकी कीर्तियां उंगलियों पर गिना सकते हैं।

दर्शक, इस प्रकार क्रिकेट का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। वह अपने साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति, आशाएं, परिकल्पनाएं लेकर खेल देखने पहुंचता है। और यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के दर्शक होते हैं। सिडनी के 'हिल' पर हर समय शोर सुनायी देता है। भारत और पाकिस्तान में हर स्टेडियम गूंजता रहता है। वेस्टइंडीज में पेड़ से लटके हुए दर्शक बहुतायत में मिलते हैं और जैसे-जैसे 'जिन' उन पर सवार होती है, गिटार व 'साम्बा' गीत बढ़ता जाता है। न्यूजीलैण्ड या केपटाउन में दर्शक चुपचाप आराम से खेल देखना पसंद करते हैं। कभी ऐसी ही शांति और खामोशी इंग्लैण्ड के क्रिकेट मैदानों पर भी पायी जाती है।

समय के साथ-साथ परिस्थितियां बदल गयी हैं। क्रिकेट संबंधी ज्ञान आज लोगों में कहीं ज्यादा है। कभी वह भी समय था जब लिण्डवाल की गेंदबाजी पर शार्टलेग, स्क्वेयर लेग, फाइन लेग और लेग स्लिप का नाम सुनकर एक अंग्रेज महिला को कहते सुना गया था, "निस्संदेह आस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी, उनके खिलाड़ियों के इतने सारे 'लेग' जो हैं।" ऐसे ही लगभग पैंतीस वर्ष पहले मैंने स्वयं कानपुर में एक सज्जन को कहते सुना था, "इस खेल से तो हमारा गुल्ली-डण्डा अच्छा है, दो दिन से यह लोग दौड़ते हैं, जाते हैं, जगह बदलते हैं और जाने क्या-क्या करते है, कुछ समझ में ही नहीं आता।" एक महिला ने मुझसे कभी पूछा था, वेस्ली हाल और गिब्ज की गेंदों की गति में क्या बहुत अंतर है ?" मुझे समय लेकर उन्हें समझाना पड़ा कि हाल तेज गेंदबाजी करते हैं और गिब्ज स्पिन गेंदबाजी। दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। परंतु आज का दर्शक बहुत समझदार और वास्तविक ज्ञाता है। उसका ज्ञान तो कभी-कभी विशेषज्ञों जैसा होता है। वह खेल की हर बारीकी को पकड़ता है और तमाम गतिविधियों का भरपूर मजा लेता है।

ऐसे दर्शको के सामने कौन खिलाड़ी नहीं खेलना चाहेगा। दर्शकों की तालियों से उसका मनोबल बढ़ता है, उनकी आलोचना से वह और दृढ़प्रतिज्ञ बनता है और उनका सहयोग उसे और अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता है। खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच एक मानसिक तंत्र जुड़ा होता है। दोनों एक दूसरे की 'वेव लेंथ' को खूब समझते हैं और इस प्रकार मनोरंजन को भरपूर बनाते हैं।

परंतु इसी के विपरीत अगर दर्शक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, उस 'वेव लेंथ' का उल्लंघन करे जिसकी आवश्यकता सदैव ही रहती है, तो खेल मनोरंजन न रहकर एक विडंबना बन जाता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस प्रकार का व्यवहार प्राय: सभी देशों में पाया जाता है। इंग्लैण्ड, भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में अकसर दर्शक मैदान में घुस आते हैं, चाहे वह मौका किसी के शतक या अर्धशतक का हो, किसी की गेंदबाजी का हो या अंपायर के निर्णय के विरुद्ध हो, खिलाड़ियों का मानसिक संतुलन किस बुरी तरह प्रभावित होता है, यह कदाचित वे ही लोग बाद में समझ सकते हैं। अंपायर का काम कितना कठिन है, यह सभी जानते हैं। फिर भी इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों दिखायी देती है ?

दर्शक अपनी आशायें साथ लाते हैं, उनके पूर्वानुमान को जहां धक्का पहुंचा, बस उनमें रोष पैदा होता है, उनमें आक्रामक व्यवहार दिखायी देने लगता है। दर्शक कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो खेल के शौकीन, कुछ खेल के कीड़े, कुछ तमाशबीन, कुछ सबकी देखा-देखी अनुकरण करने वाले और कुछ दाव लगाने वाले। खेल के कीड़े या शौकीन कदाचित सीमायें नहीं लांघते, परंतु शेष वर्ग के लोग कभी भी धैर्य या संतुलन खो सकते हैं। क्रिकेट का खेल ऐसा है जिसमें ऐसे अवसर अकसर आते हैं जब विवादास्पद घटना होती है, या खिलाड़ी दर्शकों की आशाओं को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे अवसरों पर बोतल फेंकना, अश्लील भाषा का प्रयोग और अन्य असाधारण व्यवहार, कुंठाग्रस्त दर्शकों में खूब देखने को मिलते हैं। यह क्षणिक है, तात्कालिक भी है, इसलिए इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। चाहे वह बंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद हो, लाहौर, करांची या इस्लामाबाद हो, पोर्ट आफ स्पेन, किंग्स्टन या सिडनी हो ? ओवल, लीड्स या लार्ड्स हो, हर मैदान पर ऐसी घटनायें होती हैं और बढ़ती जा रही हैं।

प्रश्न इस प्रकार के व्यवहार पर नियंत्रण रखने का है। लाखों रुपए जहां लगे हों, विदेश से जहां खिलाड़ी आये हुए हों और जहां हजारों दर्शक शांतिपूर्ण ढंग से खेल देख रहे हों, वहां कुछ असामाजिक व असंतुलित लोगों का व्यवहार मनोरंजन को क्यों समाप्त करे। अभी हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए इंग्लैण्ड ने पुलिस की सहायता ली और कठिन दण्ड नियम बनाये। मामला काफी हद तक नियंत्रण में रहा। रिलायंस कप में भारत और पाकिस्तान के लिए यह चुनौती है। प्रवेश के समय बहुत कठिन जांच की आवश्यकता है, हर स्टैण्ड में पुलिस व रक्षा कर्मचारियों की उचित व्यवस्था हो और नियमों का उल्लघंन करने पर कठिन दण्ड की व्यवस्था की जाये। मेरी समझ से अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जायेगा। दर्शक खेल देखने में रुचि रखता है, न कि खेल बिगाड़ने में, थोड़ी-सी सूझ, व्यवस्था और पूर्वानुमान से दर्शकों की उत्तेजना को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। अवश्य ही प्रबंधकों ने इस अहम मसले पर ध्यान दिया होगा।

—मनीष देव

प्रकार के
ड़े, कुछ
ले और
कदाचित
धैर्य या
अवसर
खिलाड़ी
सरों पर
साधारण
हैं। यह
पहले से
क्ता या
र्ट आफ
ईस हो,
रही हैं।
का है।
हुए हों
हों, वहां
रंजन को
द्ध खेलते
ड नियम
यंस कप
प्रवेश के
में पुलिस
यमों का
। मेरी
कि खेल
सी सूझ,
रास्ता
न मसले
नीष देव

ये ताज़गी, ये मोहकता...कुदरत के सिवा कहीं और कहां!

Cuticura
Lavender
Mist
A Talc Classique

लैवेन्डर
मिस्ट

एक लाजवाब टैल्क.
झलके इसमें आपका अंदाज़.

Orbit/MP.LM/169.87 H

राजीव
बनाम
गोयनका

रामनाथ गोयनका एक जुझारू व्यक्ति हैं। सत्ता से टकराने की उनकी पुरानी आदत है। उनके जूझने का सबसे बड़ा हथियार रहा है, उनका अखबार—'इंडियन एक्सप्रेस'। इस अखबार ने सरकार के भ्रष्टाचार को उघाड़ने में कभी कोताही नहीं की। लेकिन इस समय स्वयं 'एक्सप्रेस समूह' भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है। ये आरोप हाल के छापों के बाद लगे हैं। क्या ये छापे 'एक्सप्रेस' से बदला लेने की भावना से प्रेरित थे या सरकार ने आर्थिक अपराधों का पता लगाने का अपना दायित्व निभाया है? गोयनका पर लगे आरोपों में दम है या सरकार ने ये आरोप घड़े हैं? क्या इन आरोपों के कारण 'इंडियन एक्सप्रेस' के साथ सम्पूर्ण भारतीय प्रेस की साख दांव पर लग गयी है? क्या 'एक्सप्रेस' और सरकार के बीच छिड़े—युद्ध ने परोक्ष रूप से गोयनका और राजीव गांधी के बीच सीधी लड़ाई का रूप ले लिया है? इसका परिणाम क्या होगा?

भविष्य दांव पर: राजीव गांधी

छाया: मन मोहन शर्मा

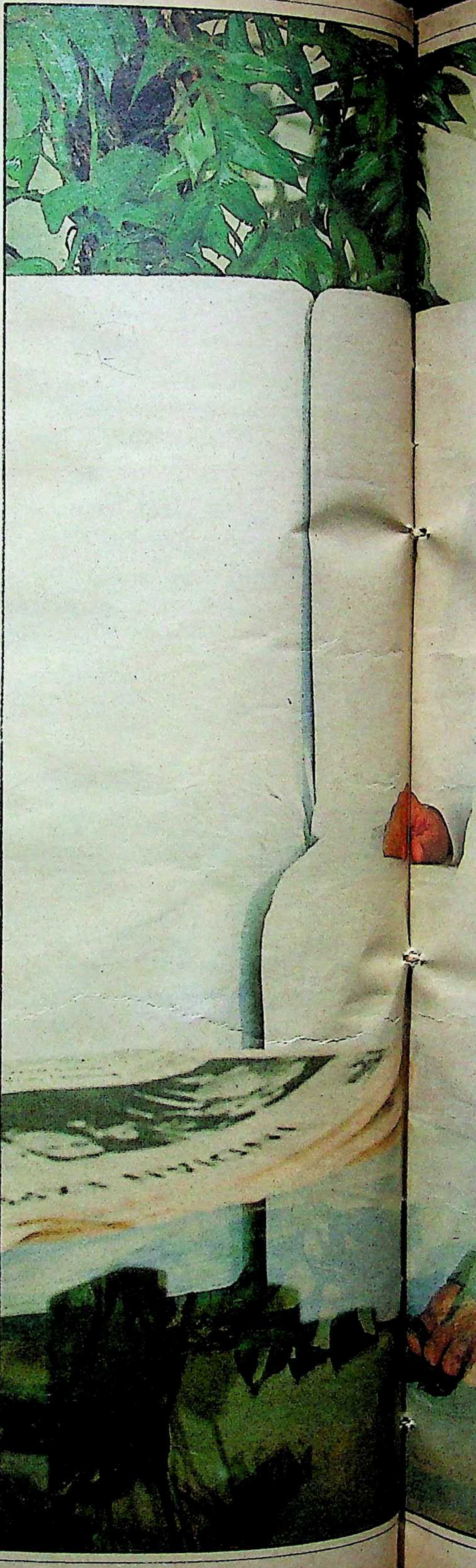

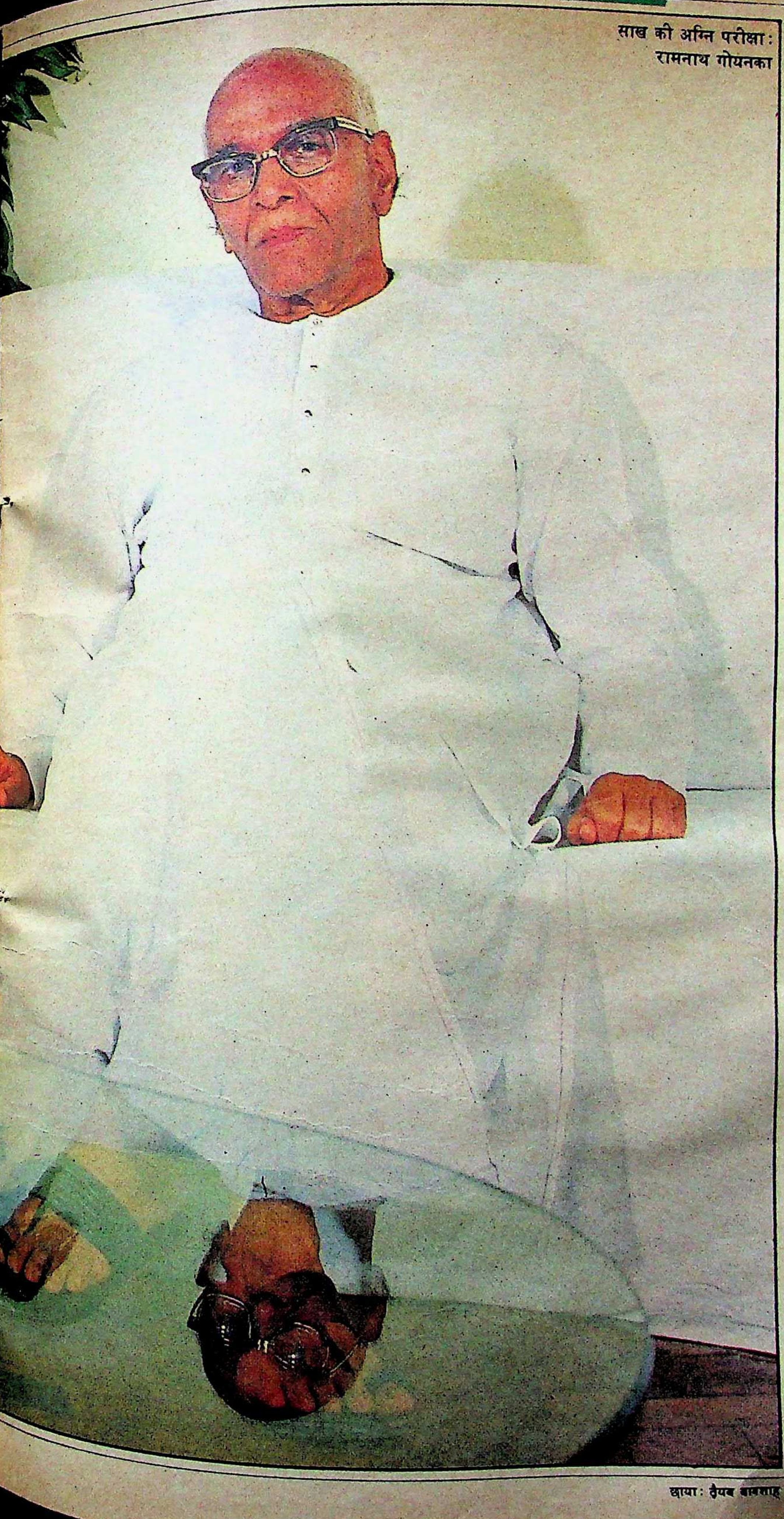

साख की अग्नि परीक्षा : रामनाथ गोयनका

सुंदर नगर के भीतरी भाग में हरे-भरे पेड़ों के बीच स्थित मकान के बाहर का शांत वातावरण महज धोखा था। भीतर स्थिति बिलकुल विपरीत थी। टेलीफोन की निरंतर घनघनाहट, संदेशों, आदेशों की बौछार, बैठकों-पर-बैठक, जिनमें अंदर-बाहर जाने की हलचल, कानून की मोटी-मोटी किताबों के अंबार, कमरों की अस्तव्यस्तता—यह माहौल, तनाव और छिड़ी लड़ाई का उतना ही मूक गवाह था, जितनी नींद से बोझिल लालिमा भरी एस० गुरुमूर्ति की आंखें, जिन्हें एक सप्ताह से भी अधिक समय से ३ या ४ घंटे से अधिक झपकने का मौका नहीं मिला।

मिलता भी तो कैसे ? संघर्ष कोई साधारण तो है नहीं। एक ओर हैं अपने साम्राज्य—इंडियन एक्सप्रेस की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह कटिबद्ध ८५ वर्षीय रामनाथ गोयनका, मुट्ठी भर विश्वस्त सहयोगी-सिपाहियों के साथ, तो दूसरी ओर हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए प्रयासरत भारत के प्रधानमंत्री ४३ वर्षीय राजीव गांधी, संपूर्ण सरकारी तंत्र और सलाहकार सेना के साथ। कदाचित जिस प्रकार गोयनका यह लड़ाई केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय प्रेस की आवाज को दबने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसी प्रकार राजीव गांधी न केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए, बल्कि अपनी धूमिल हुई छवि को फिर से निखारने के लिए भी लड़ रहे हैं।

कांटे की लड़ाई : दोनों के लिए ही यह कांटे की लड़ाई है। दांव पर एक चीज और लगी है, वह है बरसों के अथक परिश्रम से बनायी गयी उस एक्सप्रेस की प्रतिष्ठा, जिसने कभी भी सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करने का मौका नहीं गंवाया है। आज जब उसे ही कठघरे में खड़ा करने की बात की जा रही है, तो क्या रामनाथ गोयनका अपने जीवन के अंतिम समय में कोई दाग लगने देंगे ? गोयनका के व्यक्तित्व से परिचित लोगों को मालूम है कि न तो वह चुप बैठने वाले हैं, न ही सरकारी हमलों से डरने वाले। प्रत्येक चुनौती ने उनके निश्चय को और सुदृढ़ किया है। एक्सप्रेस के भूतपूर्व संपादक सईद नकवी का तो यहां तक कहना है कि सरकार के इस हमले और चुनौती ने वयोवृद्ध गोयनका को और १० साल का सक्रिय जीवन प्रदान कर दिया है। अर्जित साख को बचाने का निश्चय कोई आश्चर्य की बात नहीं।

राजीव गांधी भी इसी तत्परता से संघर्ष करने के लिए विवश हैं। यदि गोयनका के लिए अतीत की रक्षा आवश्यक है, तो राजीव गांधी को भविष्य की चिंता है। उस सुनहरे भविष्य की, जिसको वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और जिसे एक 'उद्दंड' समाचार पत्र नष्ट करने पर उतारू है। राजीव गांधी के पास एक्सप्रेस को 'सबक सिखानें' और उसें रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए बाध्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। यही उनके एकाएक आक्रामक रुख अपनाने का मूल कारण है। इसीलिए उन्होंने भी इस लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति लगाने का निश्चय

छाया : तैयब बादशाह

The day Gavaskar hit his 30th century that evening Dinesh made an equally big hit.

Congrats Sunil on your 30th Century

dinesh

dinesh suitings

Unforgettable, like the occasion.

Dinesh now introduces CASUAL WOOL

Woolmark
PURE NEW WOOL

किया है—जनता को फुसलाने के लिए वह कहें चाहे कुछ भी, सचाई यही है।

पुश्तैनी दोस्ती: यद्यपि दोनों के बीच का महाभारत जनता-जनार्दन के सामने एक्सप्रेस द्वारा पिछले छह महीनों में भंडाफोड़ करने और राजीव-सरकार द्वारा मारे गये छापों (पहला १३ मार्च को, दूसरा १ सितंबर) द्वारा सामने आया है, किंतु इसकी शुरुआत कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। रामनाथ गोयनका का तो इतिहास ही सत्ता-प्रतिष्ठान से टक्करों से भरा है। १९३२ में 'इंडियन एक्सप्रेस' का तो जन्म ही ब्रिटिश सरकार का जमकर विरोध करने और कांग्रेस के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। नेहरू-सरकार से मतभेद होने के उपरांत भी कभी आमने-सामने मुकाबला नहीं हुआ। हुआ भी तो उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ, जिनके पति फिरोज गांधी कभी एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर थे और जिनके परिवार की संरक्षकता का भार रामनाथ गोयनका ने बखूबी निभाया था। इंदिरा-गोयनका संबंधों ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे, किंतु कभी भी स्थिति वर्तमान सीमा पर नहीं पहुंची। व्यक्तिगत स्तर पर दोनों एक दूसरे को उचित सम्मान देते रहे और सुलह के सभी अवसरों का उपयोग झूठी प्रतिष्ठा को आड़े न आने देकर करते रहे।

१९८३ में एक्सप्रेस (बंबई) के संपादक राहुल सिंह ने श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में षण्मुखानंद हाल में हुई कांग्रेस की बैठक के समय खाली कुर्सियों की तस्वीर छापकर श्रीमती गांधी को बहुत नाराज कर दिया था, विशेषकर इसलिए कि उन्हें (श्रीमती गांधी) यह समझाया गया था कि चित्र पुराना है। दिल्ली में जब स्वयं रामनाथ गोयनका उनका भ्रम दूर करने के लिए मिले, तो दोनों तरफ से सुलह के हाथ आगे बढ़े थे। कहा जाता है कि उस समय के राजीव के सलाहकार भी इस समझौते के पक्ष में थे। मगर आज राजीव के साथ छिड़े घमासान युद्ध के समय ऐसे हाथों के बढ़ने की आशा फिलहाल नहीं दिखती।

दोनों प्रतिद्वंद्वियों के चरित्र में हठ सबसे ऊपर है। (बाक्स देखिए) दोनों की तलवारें म्यान के बाहर निकल चुकी हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तक रामनाथ गोयनका राजीव गांधी के उन प्रशंसकों में थे, जिन्हें उनसे अनेक आशाएं थीं। 'राजीव का भारत' नामक वृत्त चित्र में उन्होंने कहा था कि राजीव के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है और अब वह चैन से सो सकेंगे। राजीव-सरकार उनके विचारों का कितना अधिक सम्मान करती थी, इसका खुलासा इसी से होता है कि गोयनका के इस कथन को भरपूर प्रचार दिया गया। प्रेम इस हद तक बढ़ा कि राजीव के दून सखा सुमन दुबे 'इंडिया टुडे' छोड़कर एक्सप्रेस के संपादक बन गये। यह नियुक्ति राजीव गांधी-गोयनका दोस्ती का चरमोत्कर्ष थी। क्योंकि अनुमान यही था कि सुमन दुबे के नेतृत्व में एक्सप्रेस राजीव पर कभी कीचड़ नहीं उछालेगा। जब ऐसा होने लगा, तो सुमन दुबे को विदा लेनी पड़ी। प्रश्न यह है कि इस आपसी स्नेह में इतना बदलाव आया तो कैसे?

टकराव में रुचि नहीं: सरोज गोयनका

तनातनी के कारण: इस विषय में कई अटकलें निरंतर लगायी जाती रही हैं। सबसे पहले तो रिलायंस-अंबानी पर किये गये एक्सप्रेस के जबरदस्त हमलों को राजीव सरकार ने जिस ढंग से नजरअंदाज किया, उससे यही लगा कि सरकार अंबानी के साथ है। मुकेश अंबानी का प्रायः राजीव काफिले में शामिल होना, इस बढ़ती दोस्ती का द्योतक था। स्वाभाविक है कि एक्सप्रेस तथा सरकार अनायास एक दूसरे के विरोधी शिविरों में खड़े हो गये।

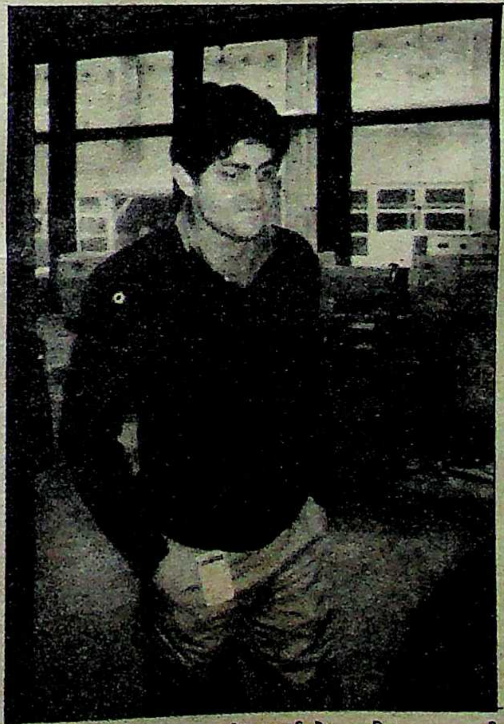
आरोप का एक कारण: रेणुशर्मा के भाई अरुण शर्मा

संयोगवश, १४ नवंबर, १९८६ को गोयनका इस्राइल में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लेने के पश्चात जब लंदन होते हुए स्वदेश वापस लौटे, तो उनके तेवर बदले हुए थे। जनसत्ता के संपादक और गोयनका के पुराने सहयोगी प्रभाष जोशी का कहना है कि लंदन में हुई एक घटना ने रामनाथ गोयनका के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचायी। एक अनौपचारिक बैठक में किसी ने भारतीय नैतिकता की खिल्ली उड़ाते हुए प्रधानमंत्री पर सीधे-सीधे आरोप लगाये थे, जिनके कारण गोयनका को नीचा देखना पड़ा था। श्री जोशी के अनुसार रामनाथ गोयनका का हृदय-परिवर्तन उसी समय शुरू हुआ था। भारत लौटते ही उन्होंने छानबीन आरंभ कर दी थी। इसी बीच अरुण शौरी को एक्सप्रेस में वापस लाकर गोयनका ने आक्रामक मुद्रा अपनाने का संकेत दे दिया। हालांकि उस समय यह माना जाता था कि सुमन दुबे ने न केवल अपने साढ़ू का मेल गोयनका से कराया था, बल्कि वह शौरी को 'टाइम्स आफ इंडिया' जो उस समय सरकार के बहुत खिलाफ था, से निकाल कर एक्सप्रेस को मजबूत करने के लिए लाये थे। मगर, घटनाक्रम इसके पश्चात कुछ ऐसा घूमा कि पहले वी०पी० सिंह, फेयरफैक्स कांड सामने आया, फिर पनडुब्बियों और बोफोर्स की तोपों ने धमाका मचा दिया।

एक्सप्रेस को जांच पड़ताल करने और आवाज उठाने का मौका मिल गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें से कोई भी मसला 'इंडियन एक्सप्रेस' ने स्वयं नहीं उघाड़ा था, लेकिन उनके सामने आते ही वह उनकी तह में पहुंचने की कोशिश में जी-जान से जुट गया था। माहौल कुछ ऐसा बना कि सहसा सभी असंतुष्ट कांग्रेसियों व राजीव-विरोधियों के लिए एक्सप्रेस सबसे बड़ी शरणस्थली बन गया। एक मामला अवश्य एक्सप्रेस ने स्वयं उघाड़ा था—१३ मार्च को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का पत्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम। इस पत्र के प्रकाशन के साथ जुड़ी एक और महत्वपूर्ण यह खबर थी कि ज्ञानीजी का यह पत्र रामनाथ गोयनका के निर्देश पर उनके चहेते गुरुमूर्ति ने स्वयं 'ड्राफ्ट' किया था। एक्सप्रेस की सनसनीपूर्ण खबरों से परेशान राजीव-सरकार ने उसी रात गोयनका के सुंदर नगर स्थित मकान पर छापा मार और गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर, खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। तब से दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। सरकार और राजीव गांधी की रही-सही इज्जत को एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के अभिन्न मित्रों—बच्चन भाइयों—के विरुद्ध दस्तावेज छापकर नेस्तनाबूद कर दिया। शौरी ने पहले पेज पर एक विस्तृत लेख में अजिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को सीधे-सीधे चुनौती दी थी कि क्या सबूत मकान के दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं (इज दिस नाट एनफ मि० प्राइम मिनिस्टर)? हारकर राजीव गांधी को अपने अभिनेता दोस्त से इस्तीफा मांगना पड़ा। जाहिर है कि यह अपमान राजीव गांधी चुपचाप सहने वाले नहीं थे। क्योंकि वह भी समझ रहे थे कि

जो हमला बच्चन तथा अम्बानी पर हो रहा है, उसका मकसद अंततोगत्वा राजीव गांधी को घेरे में लेना है।

ईंट का जवाब सरकार ने पत्थर से दिया। संसद के मानसून, सत्र के समाप्त होते ही 'इंडियन एक्सप्रेस' के ११ संस्थानों पर एक साथ सरकारी छापे. डाले गये, जिनमें ४०० से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार का रोष और नीयत स्पष्ट थी, क्योंकि आज तक इतने बड़े पैमाने पर इतनी बारीकी के साथ किसी भी समाचार संस्थान पर छापे नहीं डाले गये हैं। अत: संपूर्ण देश में खलबली मच जाना आश्चर्य की बात नहीं।

तमाम सरकारी दलीलों के बाद भी यह बात लोगों के दिमाग में घर कर गयी है कि छापे एक्सप्रेस को 'नानी याद दिलाने' की भावना से ही डाले गये हैं, यद्यपि राजस्व खुफिया निदेशालय (डी०आर०आई०) के महानिदेशक बी०वी० कुमार इस दृष्टिकोण से पूर्णतया असहमत हैं (साक्षात्कार देखिए)। कुमार का दावा है कि यह केवल कस्टम कानून, विदेशी मुद्रा नियमन कानून, आयात-निर्यात नियंत्रण कानून और उनके तहत बनायी गयी नीतियों के व्यापक उल्लंघन किये जाने के संकेत मिलने के कारण डाले गये थे और प्राप्त दस्तावेजों ने इसकी पुष्टि की है। यही नहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह गोयनका का पहला अपराध नहीं है; १९७०.में एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। कुमार के अनुसार उनका झगड़ा गोयनका के व्यापारिक धंधों से है, उनकी पत्रकारिता से नहीं। क्या उनके घोटालों, आर्थिक अपराधों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाये कि वह एक अखबार के मालिक हैं? स्वयं राजीव गांधी ने भी पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यही पूछा था कि क्या अखबार-मालिकों के लिए अलग कानून हैं। सरकारी सूत्रों को सर्वाधिक रोष इस बात का है कि दिल्ली में उनके काम में बाधा डाली गयी—जानबूझ कर। एक प्रवक्ता के अनुसार जो छह घंटे गुरुमूर्ति को उलझाये रखा—बेबुनियाद कानूनी बहस में—उस बीच न जाने कितने ही दस्तावेज इधर-उधर या नष्ट कर दिये गये होंगे। कुमार कहते हैं कि गुरुमूर्ति ने इसलिए रोके रखा, क्योंकि वह कानून जानते नहीं हैं—अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने इस संवाददाता को अनेक कानूनी दस्तावेज दिखाये। न ही कुमार इस बात को मानते हैं कि अरुण शौरी इसमें शामिल न थे। वह कहते हैं कि तमाम अखबारों में छपी उनकी तस्वीरें स्वयं गवाह हैं।

तर्क अपनी जगह काफी सही जान पड़ते हैं। किंतु राजीव गांधी का यह कहना कि उन्हें छापों के बारे में मालूम भी न था, क्योंकि वह उस दिन राजस्थान के दौरे पर थे, अत्यंत बचकाना और अविश्वसनीय जान पड़ता है। छापों की जानकारी व आदेश उनके दिल्ली रहने न रहने से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि यह काम पहले ही हो चुका होगा। छापों के विषय में उनकी उत्सुकता की पुष्टि इस बात से ही हो जाती है कि राजस्थान-यात्रा के दौरान उन्होंने

रामनाथ गोयनका की शख्सीयत

वह मजेदार व्यक्ति और एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ओछे हैं और दुश्मन के रूप में बहुत खराब—ये विचार हैं, एक भूतपूर्व वरिष्ठ कर्मचारी के, जिसने १० साल तक रामनाथ गोयनका के यहां कार्य किया है और जिसके मन में गोयनका के प्रति कोई राग-द्वेष नहीं है। लेकिन दूसरे कर्मचारी भी इतने उदार और निर्लिप्त हैं—ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल राजस्व खुफिया निदेशालय के लिए जिन लोगों ने 'स्वेच्छा' से 'मुखबरी' की है, वे एक्सप्रेस समूह में या तो कार्यरत हैं या फिर कभी कार्यरत थे। बहरहाल हर मैनेजमेंट की भांति एक्सप्रेस ढांचे में भी अच्छी और बुरी बातें हैं। गोयनका जो 'बीड़ा' उठाते हैं, उसके लिए तो वह जो चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए वह खर्च करने की खासी सावधानी बरतते हैं। "वह आने-पाई का हिसाब रखते हैं"—प्रशासन में वरिष्ठ पद पर बैठे एक व्यक्ति ने बताया। उन्होंने आगे कहा, "यदि गोयनका उत्तेजित हो जाते हैं, तो फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा और चाहे कितना ही करीब क्यों न हो, बेहद निष्ठुरता से पेश आते हैं।"

इस संदर्भ में एक पूर्व संपादक ने एक रोचक किस्सा सुनाया। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे और एक्सप्रेस में इंदिरा गांधी के पक्ष में कोई खबर छपी थी। मोरारजी ने टेलीफोन किया। गोयनका पहले तो लीपापोती करते रहे। लेकिन देसाई तो अपने हठ के लिए मशहूर हैं ही, उन्होंने गोयनका की एक नहीं सुनी और बार-बार कहते रहे, "अगर आपका पेपर ऐसा लिखेगा, तो हमारा क्या होगा।" आजिज आकर गोयनका ने तैश में आकर कहा, "मोरारजी भाई हिजड़ों के हिमायती माने जाते हैं।" प्रधानमंत्री से ऐसी बात कहना आसान नहीं है। लेकिन गोयनका जैसे निडर व्यक्ति के लिए यह कोई नयी बात नहीं। वह खुद कहते हैं, "मैं केवल भगवान से डरता हूं, और किसी से नहीं।"

अपनी निडरता के लिए मशहूर गोयनका, जिस बात को ठीक समझते हैं, उसके लिए वह किसी हद तक लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। श्रीमती गांधी को इस बात का उस समय अहसास हो गया था, जब उन्होंने आपातकाल के दौरान गोयनका को छेड़ा था। श्रीमती गांधी ने एक्सप्रेस के लिए एक निदेशक मंडल की स्थापना की थी। जब गोयनका को यह पता चला, तो उन्होंने उस मंडल को निरस्त कर दिया और अपना निदेशक मंडल बना दिया।

आपातकाल के दौरान एक बार के०के० बिडला ने सरकार और गोयनका के बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। वह गोयनका को तत्कालीन सूचनामंत्री विद्याचरण शुक्ल से मिलाने के लिए ले गये थे। आत्मदर्प से आप्लावित शुक्ल ने डींग मारते हुए कहा था, "मैं आपको और आपके एक्सप्रेस को नेस्तनाबूद कर सकता हूं।" यह सुनना था कि गोयनका ने शुक्ल पर चुनींदा गालियों की बौछार की और बाहर निकल आये। बिडला स्तब्ध होकर देखते रह गये।

दरअसल, गोयनका की लड़ाका प्रवृत्ति और संकल्प शक्ति का आभास तो बचपन में ही उस समय मिल गया था जब वह कलकत्ता छोड़कर मद्रास भाग आये थे। उस समय वह आजादी के आंदोलन से जुड़े थे। कपड़ों के व्यापार में लगा उनका परिवार उनकी इस विद्रोही मनोवृत्ति से काफी भयभीत था। जैसा कि वह कहते हैं, "मद्रास वह केवल एक 'लोटा' लेकर आये थे। वहां उन्होंने १९३२ में एक छोटा अखबार निकाला, जो आज राष्ट्रीय दैनिक के रूप में ११ स्थानों से निकलता है।"

वह धनी जरूर हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। वह बहुत शांत जीवन जीते हैं। वह सिनेमा, होटल, रेस्त्रां, पार्टियों में कभी नहीं जाते। वह पुराने मूल्यों के विश्वासी हैं और उनकी जिंदगी का एक मात्र मकसद उनका अखबार लगता है। वह केवल एक चीज चाहते हैं-अपना 'आजाद' अखबार।

क्योंकि वह आत्मनिर्मित हैं, शायद इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं करते। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, "मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मैं अपने बलबूते पर काम करने में विश्वास करता हूं।"

इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने ऐसी मजाल की। लेकिन अभी तक गोयनका का बाल बांका नहीं हो सका। उनका पक्का यकीन है कि उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता—डा० ब्राइनर और 'फेरा' उल्लंघन के मामले में भी नहीं।

जैसा कि जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी कहते हैं, "एक्सप्रेस एक अखबार से बड़ी चीज है—वह एक मकसद है और रामनाथजी एक व्यवसायी ही नहीं हैं, वह एक योद्धा भी हैं।"

यह तो नहीं कहा जा सकता कि गोयनका अछेद्य कवच से लैस हैं, क्योंकि वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति हैं और अपना अभीष्ट पूरा करने के लिए वह औना-पौना करते हैं, क्योंकि आखिरकार वह एक व्यवसायी हैं। लेकिन चाहे वह कितने ही अलोकप्रिय हों, एक बात जरूर है कि उन्होंने भारतीय प्रेस को एक नयी जान दी है। जब गोयनका किसी मकसद के लिए लड़ते हैं, तो फिर इंडियन एक्सप्रेस के पाठकों की सुबह निर्जीव कभी नहीं हो सकती।

अपने निजी सचिव पी० जार्ज को हेलीकाप्टर में ही बराबर जानकारी लेते रहने की दृष्टि से छोड़ दिया था। एक विश्वसनीय सूचना के अनुसार वित्तमंत्री और वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी अवश्य न थी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले जब वित्तमंत्री के पास फाइल गयी थी और उनकी राय मांगी गयी थी, तो उन्होंने छापों से होने वाले राजनीतिक दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए छापे न डालने की सलाह दी थी। उस समय तो छापे नहीं पड़े, किंतु जब दोबारा छापा डालने की योजना बनी, तो उनको सूचना नहीं दी गयी। शायद जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आदेश ऊपर से आ रहे थे।

प्रेस को चेतावनी: एक्सप्रेस अधिकारी आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें न केवल एक्सप्रेस की बोलती बन्द करने का प्रयास मानते हैं, बल्कि संपूर्ण भारतीय प्रेस को दी गयी चेतावनी समझते हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि एडिटर्स गिल्ड की हाल की एक बैठक में एक्सप्रेस की ओर से पुरजोर सफाई देते हुए प्रधान संपादक अरुण शौरी ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कहा कि सभी आरोप बाल की खाल निकालने की कसरत मात्र हैं। केवल एक संपादक को छोड़ (नाम जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है) अन्य सभी मौजूदा संपादक अरुण शौरी से पूर्णतया सहमत थे। यही नहीं, इस खबर पर भी चिंता प्रकट की गयी कि 'स्टेट्समैन' पर भी नजर रखी जा रही है और उसके प्रबंध निदेशक सी०आर० ईरानी से पूछताछ की गयी है। खबर मिली है कि राजधानी की एक जानी-मानी पाक्षिक पत्रिका के संपादक को भी बुलाकर "समझाया-बुझाया" गया।

एक्सप्रेस पर छापे के अन्य कारणों के बारे में प्रभाष जोशी का कहना है कि सरकार को शक था कि एक्सप्रेस के पास वे दस्तावेज हैं जो बोफोर्स सौदे में कुछ बड़े लोगों के शामिल होने की बात साबित कर सकते हैं। इधर अरुण शौरी ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक अनिल कुमार को पत्र द्वारा यह सूचित किया कि उनके पास बच्चन भाइयों के बैंक अकाउंट सहित अन्य दस्तावेज हैं, जिनसे उन पर लगाये आरोपों की पुष्टि होती है। इन दस्तावेजों और अरुण शौरी के सूत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए ही छापे के दौरान टैलेक्स कमरे और वर्गीकृत विज्ञापन विभाग में भी खोजबीन बारीकी से की गयी, ऐसी एक्सप्रेस वालों की धारणा है।

पूर्वाभास: अपनी सफाई में एक्सप्रेस परिवार सबसे पहले यही दलील देता है कि सत्ता के खिलाफ सालों से खुला अभियान चलाते समय उसे भलीभांति मालूम था कि उस पर पलट कर हमला किया जायेगा। इसलिए वह स्वयं ऐसे काम किस प्रकार कर सकता था, जिनके कारण उसके हथकड़ियां पड़ जायें। प्रभाष जोशी का तो कहना है कि सान पर काठ की नहीं, लोहे की तलवार ही चढ़ती है। उनके अनुसार देश को झकझोर देने वाले घोटालों के संबंध में कोई कार्यवाही न कर एक्सप्रेस को परेशान करने का प्रमुख कारण यही है कि सरकार ने तय कर लिया है, वह चोर को नहीं

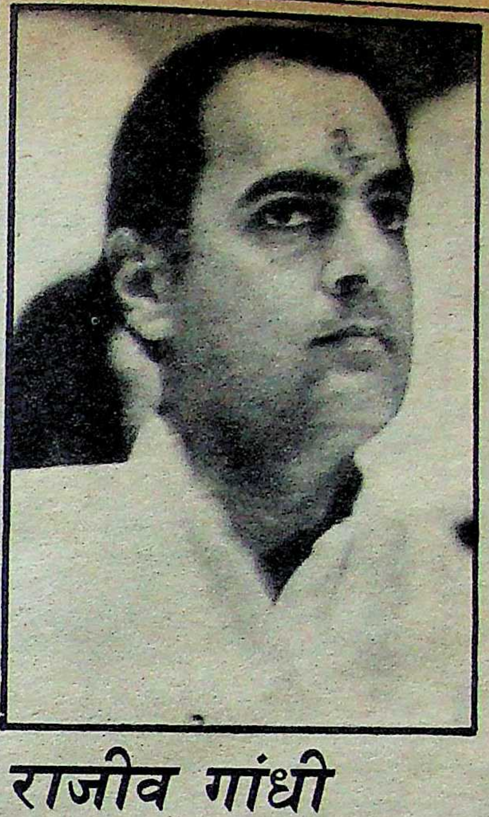

राजीव गांधी

भारतीय ढांचे के सामंती झुकाव को देखते हुए राजीव गांधी का सत्ता और सत्तारूढ़ दल का उत्तराधिकारी होना स्वाभाविक है। यह पारिवारिक विरासत उनकी ऐसी शक्ति है, जिसका मुकाबला कोई भी विपक्षी नेता नहीं कर सकता। यदि आज राजीव कमजोर दिखायी दे रहे हैं, तो इसका कारण है, उनका १९८७ का रूप जो १९८१ के राजीव से बिलकुल अलग है। आज के राजीव उन लोगों को निश्चित रूप से विलग लग रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रवेश को नेहरू की सफेद टोपी की वापसी के रूप में देखा था। इन लोगों के लिए यह सफेद टोपी राजीव गांधी की दुग्ध धवल छवि का प्रतीक थी। यह बात दूसरी है कि कुछ लोग राजीव गांधी की राजनीतिक परिपक्वता और मेधा के प्रति शंकालु थे। पब्लिक स्कूल के खास माहौल में राजीव के पले-बढ़े होने के कारण इन लोगों को लगता था कि वह भारतीय परंपराओं के अनुसार शायद अपने को न ढाल पायें। कुछ को यह भी शक था कि राजीव गांधी की जीवन शैली पाश्चात्य रही है और उनमें काकपिट में बैठकर कमांडरी करने की आदत रही है, इसलिए शायद वह छोटे कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य न बिठा पायें। लेकिन कुछ समय तक अपनी मां और पार्टी के बीच संपर्क सूत्र का काम करने के बाद वह युवा आंदोलन के नेता के रूप में उभरे थे—यानी पुरानी पीढ़ी से नयी पीढ़ी को सौंपे जानेवाले नेतृत्व के सेतु के रूप में उनको देखा जाने लगा था। उनके सहायक अकसर कहते थे कि देश की दो तिहाई जनसंख्या २० से ४० वर्ष के आयुवर्ग की है।

मैनेजरी तौर-तरीके, कंप्यूटरीकरण और सफारी-सूट का चलन, उच्च-मध्य वर्ग के दोस्तों को नौजवान राजीव द्वारा राजनीति में लगाना आदि बातों को सभी ने स्वीकार लिया था, क्योंकि राजीव को विरासत में मिले चुनाव जीतने के चुंबकीय गुणों का कांग्रेसियों को अहसास था। १९८४ के चुनावों में कांग्रेस-इ के बूथों पर जुटी भीड़ ने इसकी पुष्टि कर दी। उस समय सभी लोगों को राजीव का लोहा मानना पड़ा। राजीव के नाम पर नाक-भौंह सिकोड़नेवाले लोगों में परिगणित कुलदीप नैयर को भी कहना पड़ा था, "वह (राजीव) नेहरू हैं।"

इसी तरह के उद्गार अन्य लोगों के भी थे जिनमें राजीव गांधी की गतिशीलता, दृष्टि और उनके उज्ज्वल भविष्य का बखान था। लेकिन तीन साल गुजर जाने के बाद राजीव गांधी का वायदे पूरा करने का खाता खाली और विवादों का खाता लबालब भरा दिखायी देने लगा है।

अपने आलोचकों और विरोधियों से जूझते हुए आज राजीव गांधी ऐसे लगते हैं, जैसे उन्होंने अपवित्र गठबंधनों से दूर रहने और अवसरवादियों से दूरी बनाये रखने की क्षमता खो दी है। जटिल मुद्दों के राजनीतिक समाधान तलाशने और चुनौतियों को राजनीतिक तरीकों से खतम करने के बजाय उन्होंने अपनी सरकार और साथियों को छूट दे रखी है कि वे ताकत का इस्तेमाल करें। पथराव और काले झंडे साइमन कमीशन के समय से विपक्ष के हथियार रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी और गुस्से में हो, तो वह कभी इतिहास नहीं पढ़ता।

राजीव गांधी इस समय ऐसे लोगों से घिरे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उनके रक्षक होने का दावा कर रहे हैं। सत्ता के दलालों का जमघट फिर दिखायी देने लगा है। वटवृक्ष के नीचे घास जम गयी है।

राजीव के एक पुराने और करीबी मित्र जो अब भी उनके हितैषी हैं, का निष्कर्ष है, "राजीव कभी झुके नहीं और न उन्होंने कभी 'न' पसंद की है, जबकि धारणा इसके विपरीत है।" वह दोस्त अफसोस के साथ कहते हैं, "सब ठीक-ठीक चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हठ के कारण अपनी शक्ति को क्षीण होने दिया, उस शक्ति को जो उन्हें भावावेग में दी गयी थी।" यह भी उतना ही सही है कि राजीव गांधी जुझारू नहीं हैं और न ही धैर्यशील, जबकि ये दोनों सत्ता को दीर्घजीवी बनाने के लिए आवश्यक हैं और गोयनका जैसे विद्रोही से जूझने के लिए जरूरी।

साक्षात्कार/रामनाथ गोयनका

मैं ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरता

माया: क्या आप अचानक छापों की चपेट में आ गये? जिस प्रकार एक्सप्रेस राजीव सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए था, उसे देखते हुए आपको इस बात का अंदेशा जरूर रहा होगा कि छापा पड़ सकता है।

गोयनका: मैं अचानक किसी चपेट में नहीं आता। निश्चित रूप से यह छापा भी ऐसा नहीं था। मुझे भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की विरोधी सरकारों का सामना करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

माया: क्या (इंडियन एक्सप्रेस में) अनियमितताएं हुई हैं? इस सबका नतीजा क्या होगा?

गोयनका: डी॰आर॰आई॰ ने इंडियन एक्सप्रेस पर गलत कार्यों के आरोप लगाते हुए तीन प्रेस वक्तव्य जारी किये। हमने हर आरोप का मुद्देवार उत्तर दे दिया है। एक बात निश्चित है कि इन प्रेस-वक्तव्यों का मकसद इस तथ्य को छिपाना था कि डी॰आर॰आई॰ ने कोई अनियमितता नहीं पायी है। अधिकांश मामलों में प्रेस वक्तव्य ने उन्हीं बातों को सूचीबद्ध कर दिया है, जिन पर इंडियन एक्सप्रेस तथा सरकार के बीच अनेक वर्षों से विवाद चला आ रहा है और ये सब बातें बैलेंस शीट, अधिकारियों से हुए पत्राचार एवं अधिकारियों के पास विचाराधीन कानूनी मामलों में पूरी तरह उजागर हैं। मैं डी॰आर॰आई॰ को चुनौती देता हूं कि वह बताये कि उसने इन छापों में क्या पाया? यह ऐसा अभियान था, जिसमें एक दर्जन केंद्रों पर चार सौ से अधिक सरकारी अधिकारियों को दौड़ाया गया था। अब यह तय करना जनता का काम है कि ये सब बातें क्या संकेत देती हैं?

माया: क्या यह सच है कि रेणु शर्मा को जानकारियां प्राप्त करने के लिए डराया-धमकाया गया? इस मामले से उसका संबंध और भूमिका क्या है?

गोयनका: अन्य लोगों की तरह ही मैंने सिर्फ समाचार पत्रों में ही पढ़ा कि रेणु शर्मा को वक्तव्यों पर हस्ताक्षर करने के लिए डराया-धमकाया गया जो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वह इस संगठन की भूतपूर्व कर्मचारी थीं और मुख्यतः मेरे दिल्ली कार्यालय में काम करती थीं।

माया: ऐसा आरोप है कि इन सब बातों के पीछे रिलायंस और अमिताभ का हाथ है। ऐसा कहा जाता है कि मित्र-पत्रकारों के बीच एक्सप्रेस के खिलाफ परचे बांटे गये थे। क्या आप समझते हैं कि एक्सप्रेस द्वारा छेड़े गये जेहाद के जवाब में ऐसा किया गया?

गोयनका: मैंने भी सुना था। मैं नहीं जानता कि वह अंबानी था या अमिताभ, लेकिन किसी ने एक्सप्रेस के खिलाफ आरोपों से संबंधित एक पुस्तिका वितरित की थी। मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की और न ही मैं इन छापों से परेशान हूं। यदि इन सबके पीछे अंबानी या अमिताभ का हाथ है, तो इससे उनकी ताकत का पता चल जाता है, साथ ही यह भी कि सरकार किसकी बात सुनना चाहती है। मैं एक क्षण के लिए भी यह नहीं कहता कि सरकार को एक्सप्रेस पर लगे आरोपों पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि क्या सरकारं महज एक्सप्रेस पर लगे मनगढ़ंत आरोपों पर ही कार्यवाही करेगी और जनता के सामने दस्तावेजों से पुष्ट अंबानियों और बच्चनों जैसों पर लगे आरोपों पर कार्यवाही नहीं करेगी, जबकि आज तक इन्होंने उनका खण्डन तक नहीं किया है?

माया: यह आम धारणा है कि आपने रिलायंस पर हमला इसलिए नहीं बोला कि नसली वाडिया से आपके संबंध थे, बल्कि यह इस कारण किया, क्योंकि दोनों के बीच समझौता कराने के आपके प्रयासों के दौरान अंबानी आपको बराबर अपमानित करते रहे थे। क्या यह सच है?

गोयनका: यह सोचना तक बेहूदा है कि मेरी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण इंडियन एक्सप्रेस ने अंबानी इंडस्ट्रीज का परदाफाश करना शुरू किया। मुझे तो चिंता उस तरीके को लेकर है, जिसके जरिये रिलायंस कानूनों को तोड़ता रहा था और साफ बचता रहा था। जब मैंने पाया कि रिलायंस प्रेस को भी नहीं बख्श रहा, तो मैंने सोचा कि इस महान संस्थान (प्रेस) और देश के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आम जनता के सामने तथ्यों को रखूं। मुझे विश्वास है कि इंडियन एक्सप्रेस ने यह कार्य बड़ी प्रामाणिकता और सफलता के साथ किया है। यही सचाई है। इस संबंध में कोई अन्य बात यदि सच है भी, तो वह सिर्फ क्षेपक है।

माया: छापों के संबंध में एक धारणा यह है कि सरकार ने यह जानकर कि एक्सप्रेस उतना पाक-साफ नहीं है, जितना कि वह दावा करता है, उसने एक्सप्रेस के घपलों की ओर संकेत करके उसे यह पुराना सबक सिखाना समयोचित समझा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए?

गोयनका: इंडियन एक्सप्रेस को सबक सिखाने की हर कोशिश नाकाम रही है और मुझे एक अपराधी साबित करने की भी हर कोशिश असफल रही है। १९७४ में संसद में मेरे विरुद्ध उस समय एक आरोप लगा था, जब किसी ने मुझे 'पुराना अपराधी' कहा था। तब मैंने उत्तर दिया था कि मैं महात्मा गांधी के आह्वान पर ब्रिटिश सरकार के कानून तोड़ता रहा हूं और उन अर्थों में मैं वास्तव में 'पुराना अपराधी' हूं। आज जो यह सरकार कर रही है, उसी तरह श्रीमती गांधी की सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह मेरे खिलाफ कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकी थी। मैं सत्ता केंद्र के आसपास रहनेवाले उन लोगों में से नहीं हूं जो जांच-पड़ताल की संभावना से डरे हुए हैं। उन्हें अपने बचाव के लिए सरकार की जरूरत है। मैं तो सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण तरीके तक की जांच का स्वागत करूंगा। यदि मैंने कोई गलत काम किया है, तो मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं।

माया: एक्सप्रेस पर लगे आरोपों और उसके विरुद्ध जारी अभियान का इंडियन एक्सप्रेस की साख पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय प्रेस के पुरोधा होने के नाते आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रेस की प्रामाणिकता और आजादी सुरक्षित रहेगी?

गोयनका: मुझे बताइये ऐसा कौन-सा आरोप है

जो आज इंडियन एक्सप्रेस पर लगाया जा रहा है और जिसे अतीत में नहीं लगाया गया। महीनों पूर्व इंडियन एक्सप्रेस पर देश में अस्थिरता पैदा करने का आरोप' लगा था और इस सरकार के एक मंत्री ब्रह्मदत्त ने तो मुझ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप तक लगाया था। अब आरोप यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने कर-चोरी की है। हमारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। मैं खुश हूं कि वे लोग बड़े आक्रामक तरीके से जांच कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की साख कभी नष्ट नहीं की जा सकती। इसका निर्माण हमारी व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों की वजह से हुआ है। अतः प्रेस की साख पर दूरगामी प्रभाव पड़ने का आपका भय स्पष्ट रूप से निराधार है।

माया : आप भारत आनेवाली किसी भी वस्तु के लिए किसी विदेशी द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के निवेदन को कैसे जायज सिद्ध करेंगे? क्या यह 'फेरा' का उल्लंघन नहीं है? यदि ऐसा है, तो क्या आप इसे इस आधार पर उचित ठहरायेंगे कि अकसर साध्य साधनों को असंगत बना देते हैं?

गोयनका : डा० ब्राइनर कोई व्यावसायिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक महान न्यायविद् हैं और हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वह पिछले तीन दशकों से मेरे और मेरे परिवार के महत्वपूर्ण मित्र रहे हैं। उन्होंने भारत आनेवाली किसी वस्तु के लिए भुगतान नहीं किया। 'फेक्सिमिले सिस्टम' खरीदने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने एक विदेशी सप्लायर से एक सौदे का करार किया था। यह जुलाई, १९८६ में हुआ था और भुगतान सितंबर १९८६ में किया जाना था। लेकिन सरकार की ओर से तब तक इसकी अनुमति न मिलने के कारण इंडियन एक्सप्रेस वह नहीं कर सका। विदेशी सप्लायर ने तब सौदा रद्द कर देने की धमकी दी। इसका मतलब होता फिर नये सिरे से समझौता और अतिरिक्त दाम। मैंने ब्राइनर से कहा कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, जिससे यह सौदा रद्द न हो। ब्राइनर ने हमारी मदद करने की कोशिश की और जब तक कि इंडियन एक्सप्रेस एल०सी० (लेटर आफ क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर लेता और इसका भुगतान नहीं कर देता, तब तक के लिए उन्होंने सप्लायर के पास वापस मिलनेवाली राशि के रूप में दो लाख पौण्ड जमा करा दिये। डा० ब्राइनर द्वारा जमा कराया गया धन इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भुगतान किये जानेवाले धन की न तो पूरक राशि है और न ही इसके एवज में भुगतान किया गया धन है। इससे विदेशी सप्लायर के प्रति इंडियन एक्सप्रेस के दायित्व में रद्दोबदल नहीं होता। असलियत यह है कि ब्राइनर द्वारा केम्को (विदेशी सप्लायर) के पास धन जमा करा देने के बाद ही मुझे इसकी जानकारी मिली। इसमें गुप्त कुछ भी नहीं है। इसमें 'फेरा' का किसी भी तरह कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

माया : बहुत अर्सा नहीं गुजरा है, जब आप राजीव गांधी के उत्कट समर्थक थे और उनसे आपको भारी अपेक्षाएं थीं। प्रधानमंत्री ने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपको टकराव का रास्ता अपनाना पड़ा?

गोयनका : हां यह सच है कि मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थीं। मैंने खुले रूप में ऐसा कहा था। यह एक प्रकार से आस्था व्यक्त करना था। लेकिन मैं इस तथ्य से बेहद निराश हुआ कि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई संबंध नहीं है।

माया : श्रीमती गांधी को जब घेरा गया था, तो वह आपातकाल लायीं, राजीव गांधी क्या करेंगे?

गोयनका : मैं नहीं जानता कि राजीव गांधी क्या करेंगे? मैं उन्हें समझ नहीं सकता। वैसे क्या आप समझ सकते हैं?

माया : खराब स्वास्थ्य और ढलती उम्र के कारण क्या आप खास कर राजीव गांधी के हाथों में आयी सरकार की ताकत से भयभीत नहीं हैं?

गोयनका : मैं जानता ही नहीं कि भय क्या होता है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरता।

माया : क्या यह सच है, सरकार के कुछ लोग आप और आपकी पुत्र-वधू सरोज के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं?

गोयनका : यह सब बकवास है। मैं जो कुछ करता हूं, मेरी पुत्रवधू उसमें हर तरह से मेरे साथ है। समाचार पत्र ने जो रुख अपनाया है, उस पर उसे भी उतना ही गर्व है, जितना कि मुझे है।

माया : एक आम सवाल यह है कि गोयनका के बाद कौन? क्या यह सच है कि आप इस विचार को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था का नियंत्रण परिवार के सदस्यों—पुत्रवधू और पौत्रों को सौंप दिया जाये और संपादकीय विभाग के नियंत्रण के लिए शौरी और मुलगांवकर जैसे पत्रकारों का एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज बना दिया जाये?

गोयनका : मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सोचता है कि मेरे बाद प्रलय आ जायेगी। मेरे दोनों पौत्रों—विवेक खेतान और मनोज सेंथालिया—ने गत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से अच्छा काम किया है। वास्तव में मैं सक्रिय रूप से व्यवसाय की देखभाल कर ही नहीं रहा हूं। मुझे विश्वास है कि समाचार पत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र रहेगा। वहां समर्पित लोगों की अच्छी टीम है जो मेरे बाद समाचार-पत्र को संभालेगी।

—रंजना कक्कड़

पकड़ेगी— "हमारी पुलिस को चोरी की चिंता नहीं है, उसे चौकीदारों के चिल्लाने का डर है।"

किंतु यदि स्वयं चौकीदार ही चोरी करे, तो पुलिस क्या करे? क्योंकि वह रक्षक है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाये? ऐसे कितने ही प्रतिप्रश्न सरकार की ओर से उठाये जा रहे हैं। जहां तक एक्सप्रेस का प्रश्न है, समस्या और भी गंभीर तथा जटिल है, क्योंकि नैतिकता का प्रश्न और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में पहल करनेवाला वह स्वयं ही है। लेकिन अब पासा पलट गया है और दूसरों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले एक्सप्रेस को फिलहाल अपने पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा साबित करना होगा। राजीव गांधी द्वारा अपनायी गयी रणनीति की सफलता भी इसी में है कि वह एक्सप्रेस को ज्यादा-से-ज्यादा रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए विवश करें, ताकि उनकी सरकार पर नित्य नये हमले में जुटा एक्सप्रेस अपना अधिक-से-अधिक समय व शक्ति अपनी सफाई देने में व्यतीत करे। लेकिन जरूरी नहीं कि घटनाक्रम की यही दिशा हो। संभव है कि इस सरकारी कोशिश का प्रभाव और उलटा हो जाये। कम-से-कम फिलहाल गोयनका की त्रिमूर्ति—जेठमलानी, अरुण शौरी गुरुमूर्ति—का रवैया रामनाथ गोयनका से बंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा की गयी ६० मिनट की पूछताछ के ४८ घंटे पश्चात और ज्यादा आक्रामक व आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लगता है कि जैसे-जैसे सरकार यह हमला तेज कर एक्सप्रेस को बचाव की मुद्रा में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वैसे-वैसे इस त्रिमूर्ति ने और ज्यादा आक्रामक रुख अपना कर सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। यह रणनीति गोयनका की कार्यशैली का अभिन्न अंग है। आपातकाल में गोयनका द्वारा अपनायी गयी इसी रणनीति ने उन्हें ७७ में सफलता व शक्ति दिलवायी थी। देखना है कि मां के विरुद्ध जिस रणनीति ने गोयनका को सफलता दिलायी थी, क्या वह रणनीति बेटे के विरुद्ध भी उन्हें विजय का सेहरा पहना पायेगी।

तर्क-विवाद कुछ भी हों, कारण चाहे व्यक्तिगत हों या राजनीतिक, आर्थिक भ्रष्टाचार के हों या बदले की भावना के, परिणाम एक ही है—घमासान युद्ध। हो भी यही रहा है कि अपने-अपने क्षेत्र के दो महारथी कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर आये हैं। एक के हाथ में है कलम, दूसरे के हाथ में है सत्ता की तलवार। दोनों ही एक दूसरे को घायल करने में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। दोनों ही पक्षों की शक्ति और सत्ता का आधार जनमत में बनी उनकी साख है। यदि राजीव गांधी की साख एक्सप्रेस द्वारा पिछले महीनों में चलाये अभियान द्वारा क्षतिग्रस्त हुई है, तो छापों और सरकारी आरोपों ने एक्सप्रेस की साख पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। सवाल अब केवल अंतिम हार-जीत का है। उस लड़ाई की हार-जीत का जो केवल दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत अहं के टकराव से शुरू भले ही हुई हो, लेकिन जिसके परिणाम का प्रभाव संपूर्ण

साक्षात्कार/**बी०वी० कुमार** निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय

छापा समाचार पत्र पर नहीं, गोयनका की व्यावसायिक गतिविधियों पर मारा गया था

माया: इंडियन एक्सप्रेस के मामलों की कब से जांच की जा रही थी?

बी०वी० कुमार: हमें राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) में अगस्त १९८७ के पहले हफ्ते में सूचना प्राप्त हुई थी। इससे भी काफी पहले, लगभग ८-९ माह पूर्व, हमें अनेक शिकायतें सीमा-शुल्क की चोरी, आयात और अन्य नियमों के उल्लंघन के बारे में प्राप्त हुई थीं। शिकायत करने वालों में कुछ सांसद तक शामिल थे और उसी समय से हमने अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर सामान्य जांच शुरू कर दी थी कि आयात नियंत्रण कानूनों के अधीन लागू शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं। इन जांचों से संकेत मिला कि एक्सप्रेस समूह द्वारा आयात नियंत्रण कानून की शर्तों का पालन नहीं किया गया। किंतु मात्र यह तलाशी वारंट की तामील के लिए काफी नहीं था। बाद में जब हमें अगस्त के पहले हफ्ते में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, तो हमने प्राप्त सामग्री की प्रामाणिकता की जांच की। हमें पता चला कि आरोपों में कुछ तथ्य है, इसलिए हमने फौरन कार्रवाई करने की योजना बनायी।

माया: आरोप है कि इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित एक गुप्त दस्तावेज, जिसकी एक प्रति इंडियन एक्सप्रेस के बंबई कार्यालय में शायद प्राप्त हुई थी, पहले से ही सब जगह घूम रहा था। क्या यही आपकी जानकारी का आरंभिक स्रोत था?

कुमार: नहीं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमें जिम्मेदार सांसदो से सूचना प्राप्त हुई थी। बाद में हमें ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों से उनके 'लेटर हेड' पर लिखी जानकारी मिली और उसके काफी बाद हमें खास आरोप प्राप्त हुए, जिनके आधार पर व्यापक जांच की गयी और तभी तलाशी की कार्रवाइयां की गयीं।

माया: कहा जाता है कि डीआरआई द्वारा दर्ज आरोपों के अनेक वाक्य तक उस गुप्त दस्तावेज से ज्यों-के-त्यों लिये गये हैं।

कुमार: मैं इसे सच नहीं मानता। आप उल्लंघनों को देखें, तो ज्ञात होगा कि उनका संबंध मशीनरी की कीमत कम करके बताना, किन्हीं अज्ञात विदेशी सूत्रों से विभिन्न सप्लायरों को अदायगी और आयात-उपरांत नियमों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि जिस मशीनरी को पूंजीगत सामान के रूप में 'ओपेन जनरल लाइसेंस' (ओ जी एल) के तहत आयात किया गया था, उसे दूसरी कंपनी को बेचा गया जो आयात-नियंत्रण कानूनों का सरासर उल्लंघन है। अखबारी कागज की रद्दी के रूप में बिक्री तथा आयकर नियम के उल्लंघनों के अन्य मामलें भी थे।

माया: क्या ऐसा व्यापक छापा कस्टम और आयकर उल्लंघनों का पता लगाने के लिए जरूरी था? आम धारणा है कि यह आदेश जानबूझकर दिया गया, जिससे न केवल इंडियन एक्सप्रेस, बल्कि समूचे भारतीय प्रेस को आतंकित किया जा सके।

कुमार: सामान्यत: कोई डीआरआई को छापों का आदेश नहीं देता। डीआरआई को कार्रवाई का एक विशेष अधिकार है।

माया: आदेश से मेरा अर्थ डीआरआई से है। मैं यह नहीं कहती कि किसी अन्य ने डीआरआई को आदेश दिया। किन्तु क्या ऐसे व्यापक पैमाने पर छापे जरूरी थे? क्या इसके द्वारा समूचे भारतीय प्रेस को चेतावनी दी गयी है?

कुमार: आप डीआरआई की कार्रवाई रिकार्ड की जांच कर सकती हैं। हमने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ उनकी हैसियत की परवाह किये बिना कार्रवाई की है। हम सरकार की एक बहुत जिम्मेदार जांच इकाई के रूप में एक विशेष अधिकार के तहत काम करते हैं। हम तभी ऐसी अति व्यापक जांच कार्रवाई हाथ में लेते हैं, जब हमारे पास अति विशिष्ट गुप्त सूचनाएं होती हैं। मैं अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि ऐसा छापा कस्टम कानून या आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत मारना कानून की प्रक्रिया के अनुकूल है, जिसका उद्देश्य अपराध से संबंधित दस्तावेजी या अन्य प्रमाण प्राप्त करना होता है।

माया: क्या आप कोई विशेष चीज, विशेष दस्तावेज प्रमाण की तलाश में थे? अरुण शौरी ने कहा था कि उनके पास बच्चन बंधुओं के खिलाफ विशेष दस्तावेजी प्रमाण हैं।

कुमार: दरअसल हमारी कार्रवाई को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर आंका जा रहा है। हम मशीनों की कीमत कम बताने, कस्टम शुल्क की चोरी और आयात-उपरांत शर्तों तथा अन्य आर्थिक, उल्लंघनों के प्रमाणिक दस्तावेजों की तलाश में थे, क्योंकि आयकर विभाग भी हमसे संबद्ध था। हमें 'इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा की जा रही किसी विशेष जांच पड़ताल का पता नहीं था।

माया: छापे के समय से यह धारणा बनती है कि उसका किसी राजनीतिक उद्देश्य और संकट से संबंध था—मसलन संसद का समापन हो चुका था, साथ ही नसली वाडिया के कुछ लोगों के यहां भी तभी छापे पड़े।

कुमार: छापे का वक्त इस पर निर्भर करता है कि हम कब अपनी जांच और उससे संबंधित कार्रवाई को पूर्ण कर लेते हैं। देखिए इससे कुछ लेना-देना नहीं कि संसद का अधिवेशन चल रहा है या नहीं।

माया: बात यह नहीं, यह मामला समाचार पत्र का था, जहां आप छापा मारने जा रहे थे। आपको अवश्य यह चिंता हो सकती थी कि इससे संसद के भीतर-बाहर भारी होहल्ला मचेगा।

कुमार: मैं पुन: जोर देकर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि छापा समाचार पत्र पर नहीं, रामनाथ गोयनका और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर मारा गया था।

माया: इंडियन एक्सप्रेस का मानना है कि आपने जानबूझकर उसे चुना। क्योंकि वह सरकार विरोधी हैं।

कुमार: मैं नहीं समझता कि आपके आरोप में कोई तथ्य है। आप हमारी सूची देखें, तो पायेंगी कि हमने सैकड़ों कंपनियों, तस्करों के प्रतिष्ठानों आदि पर छापे मारे हैं। 'मीडिया' विशेष ध्यान केवल उन्हीं छापों पर देता है, जिन्हें वह अपने पाठकों के लिए रुचिकर समझता है। इस तरह किसी खास को चुनने का सवाल नहीं उठता। १९८५ में ६० हजार और १९८६ में ५२ हजार छापे मारे गये। १९८७ के अगस्त माह तक ३२ हजार छापे मारे गये। इनमें से कितने छापों की खबरें छपती हैं?

माया: इस प्रकार के आरोप वाडिया, अंबानी और अन्य कंपनियों के खिलाफ भी लगे थे। उन पर 'फेरा' और कस्टम उल्लंघनों के भी आरोप थे। फिर आपने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

कुमार: मुझे विश्वास है कि आपको रिलायंस समूह के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस की जानकारी होगी। बांबे कस्टम हाउस ने और बंबई मुख्य उत्पादशुल्क निदेशालय ने दो करोड़ से अधिक की ऐसी नोटिसें जारी की हैं।

माया: श्री गुरुमूर्ति ने हमसे कहा है, "हम डीआरआई को अपने आरोप सिद्ध करने की चुनौती देते हैं। वह क्या 'बयान' है, जिसकी वह बात करते हैं? डीआरआई से पूछें कि 'बयान' से उनका क्या मतलब है।"

कुमार: आर०पी० मित्तल, रेणु शर्मा, श्रीनिवास, पूर्व महाप्रबंधक, के बयान खुद गवाह हैं और ये बयान छापों के दौरान जब्त दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित हैं।

माया: क्या ये बयान धमकी देकर लिये गये?

कुमार: यह सरासर असत्य और निराधार है।

रंजना कक्कड़

राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला होगा।

दूरगामी परिणाम: यदि सरकार एक्सप्रेस पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में सफल हो जाती है, तो उसका प्रभाव न केवल एक्सप्रेस पर पड़ेगा—निश्चित रूप से उसकी बोलती बंद हो जायेगी—वरन संपूर्ण भारतीय प्रेस के प्रति जनता का आदर और विश्वास उठ जायेगा। इससे न केवल सरकार का सिर ऊंचा होगा, बल्कि स्वयं राजीव गांधी को राजनीतिक पुनर्जीवन भी मिलेगा। राजीव गांधी के लिए यह विजय प्राप्त करना, तरीका चाहे कुछ भी हो—नैतिक या अनैतिक—अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संगठित विपक्ष के अभाव में प्रेस ही विपक्ष का रूप धर राजीव गांधी के खिलाफ मुहिम चला रहा है।

इस मुहिम के नेतृत्व के अतिरिक्त 'इंडियन एक्सप्रेस' विपक्ष का भी अगुआ बना हुआ है। संसद के बजट और मानसून सत्रों के दौरान उसने अपनी यह भूमिका बखूबी निभायी है। बोफोर्स, पनडुब्बियां, अजिताभ-अमिताभ—सभी किस्सों में विपक्ष बराबर एक्सप्रेस पर निर्भर रहा है और एक्सप्रेस ही सरकार को बार-बार नीचा दिखाने में सफल रहा है। मानसून सत्र के अंतिम दिन दिल्ली के गलियारों में जोरदार चर्चा थी कि विपक्षी नेता मधु दंडवते सत्र को कुछ घंटों के लिए बढ़वायेंगे और इसी बीच विदेश से प्राप्त एक धमाकेदार समाचार एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप लड़खड़ाती सरकार गिर पड़ेगी।

इससे पहले भी खबर फैली थी कि वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद में हुई सौदेबाजी का भी पर्दाफाश होने वाला है। तीन विभिन्न तिथियों की चर्चा रही। अंत में कहा गया कि इतालवी संबंध स्थापित करने वाले कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण अभी हाथ रोक लिया गया है। किंतु शीघ्र ही

साक्षात्कार/
एस०गुरुमूर्ति

सरकार के इस खेल का भी परदाफाश करेंगे

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह के मालिक रामनाथ गोयनका के एक सिपहसालार एस० गुरुमूर्ति मूल रूप से चार्टर्ड एकांउटेंट हैं, लेकिन पत्रकार के रूप में वह रिलायंस उद्योग समूह के संबंध में लेखमाला लिखने के कारण विख्यात हुए। आज वह गोयनका के कुछ खासमखास सलाहकारों में गिने जाते हैं। राहुल देव ने एक्सप्रेस समूह पर पड़े छापों के बाद गुरुमूर्ति से विस्तार से बातें की हैं, प्रस्तुत हैं, वार्ता के प्रमुख अंश:

माया: ऐसी खबरें हैं कि छापों के बाद रामनाथ गोयनका सरकार के प्रति उदार होने का मन बना रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि संपादक भी बदला जायेगा?

गुरुमूर्ति: यह खबर शरारतपूर्ण है। छापों से समाचार पत्र और मजबूत होगा, ये इसे और बड़ा बनायेंगे। यदि सरकार की अपेक्षा है कि इससे समाचार पत्र मुलायम पड़ जायेगा, तो उसे बुरी तरह निराश होना पड़ेगा। पाठक समाचार पत्र की ताकत होते हैं। समाचार पत्र की नीतियों के कारण एक लंबे अर्से में पाठक तैयार होते हैं। संपादक या मालिक समाचार पत्र के पाठकों की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि पाठकों का मिजाज ही समाचार पत्र का मिजाज बन जाता है। मार्च, १९८७ के बाद एक्सप्रेस की प्रसार संख्या में एक लाख की वृद्धि हुई है। यदि सरकार धकमाकर इंडियन एक्सप्रेस के स्वरूप बदलने का इरादा रखती है, तो हम अपने पाठकों और पाठकों के माध्यम से पूरे देश के सामने सरकार के इस खेल का भी परदाफाश करेंगे।

माया: आपने डी०आर०आई० द्वारा लगाये आरोपों को चुनौती दी है। उन्होंने छापों में कुछ पाया या नहीं, लेकिन आपने स्वीकार किया है कि कुछ लाख का केस बन सकता है।

गुरुमूर्ति: मेरे स्वीकार करने का क्या मतलब? हमने डी०आर०आई० को चुनौती दी है कि वह आरोपों को सिद्ध करे। उन्हीं से पूछिए कि 'मेरी स्वीकृति' का क्या मतलब है?

माया: लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलानेवाला इंडियन एक्सप्रेस ही यदि अनियमितताओं का दोषी पाया जाता है, तो क्या इससे सम्पूर्ण भारतीय प्रेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा?

गुरुमूर्ति: ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस ने यह सब (अनियमितताएं) की है। उनका (सरकार) इरादा ऐसा माहौल पैदा करने का था, जिससे हमारी साख पर आंच आ सके। आज स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति के यहां एक बार छापा पड़ता है, तो यह माहौल बनाया जा सकता है कि उसने कोई-न-कोई गलत काम जरूर किया है। सरकार ने इसका लाभ उठाया। इतना ही नहीं इस मामले में सरकार ने प्रतिदिन आरोपों के बुलेटिन प्रसारित किये, जिनका दूरदर्शन और आकाशवाणी ने बड़ी उदारता से उपयोग किया, लेकिन एक्सप्रेस को निशाना बनाये जाने का यह पहला अवसर नहीं है। ऐसा 'आपातकाल' के दिनों में भी हुआ था। तब एक्सप्रेस को कानून के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता के रूप में प्रचारित किया गया था। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते। यह एक तथ्य है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम इन सब जांच-पड़तालों से मुंह नहीं छिपा रहे। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि कानून को अपना कार्य करने दिया जाये। क्या मैं स्वयं को जांच के लिए प्रस्तुत करने से इनकार कर रहा हूं? मेरी शिकायत यह है कि मेरे साथ यह सब कुछ इसलिए हो रहा है, क्योंकि मैं किसी और की छानबीन करने की मांग कर रहा हूं। यदि इंडियन एक्सप्रेस दण्ड से बचने की कोशिश करता है, तो आप कह सकते हैं कि उसका भ्रष्टाचार की ओर उंगली उठाना गलत है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया? फिर समस्या क्या है? यदि अमिताभ बच्चन का परदाफाश करने के लिए यह जरूरी है कि इंडियन एक्सप्रेस ने किन्हीं कथित ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन न किया हो, तब तो सिर्फ रामकृष्ण मिशन ही भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर बोल सकता है।

माया: ऐसा कहा जाता है कि डी०आर०आई० के वक्तव्य के कुछ हिस्से उन आरोप पत्रों से लिए गये हैं, जिन्हें अंबानी ने प्रसारित किये थे?

गुरुमूर्ति: यह सत्य है।

माया: इसका मतलब अंबानी का इसमें हाथ है?

गुरुमूर्ति: हो सकता है। अंबानी को ऐसा करने दीजिए। मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कर सकते हैं। दोष उनके दरवाजों पर नहीं है, बल्कि अधिकतर दोष तो उनके द्वार पर है जो शासन करते हैं। और जिन्होंने अपना इस्तेमाल होने के लिए अपने को खुद-ब-खुद उनके (अंबानियों) हवाले कर दिया है। सवाल यह नहीं है, कि किसने इन जाली पत्रों को गढ़ा है, महत्वपूर्ण यह है कि इनका इस्तेमाल किसने किया? इससे पता चलता है कि सरकार की स्थिति क्या है? वह अंबानियों के मुकाबले असुरक्षित है। सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि किसी ने इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ ऐसा किया था।

माया: बोफोर्स ने अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ को जो चरित्र प्रमाण-पत्र दिया है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं?

गुरुमूर्ति: इसे हमारे राजदूत के इस वक्तव्य के साथ पढ़िये जिसमें उन्होंने कहा है कि बोफोर्स विश्वसनीय नहीं है।

माया: गोयनका से आपका क्या रिश्ता है?

गुरुमूर्ति: यह ऐसे दो लोगों का रिश्ता है, जिनके एक जैसे सामाजिक मूल्य हैं। यह संबंध समान सामाजिक उद्देश्यों और आपसी समझ से विकसित होता है।

माया: क्या राजीव गांधी को सत्ताच्युत करना भी उन उद्देश्यों में से एक है?

गुरुमूर्ति: क्या भारत सरकार को गिराना संभव है। क्या भारत कोई छोटा-मोटा गणराज्य है? हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपनी बात जनता के सामने रख दी है कि वहां भ्रष्टाचार है और सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है। यह संवाद जारी है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। या तो हम अथवा वे, गलत या सही साबित हो सकते हैं। अतः सरकार का तख्ता पलटने का सवाल ही कहां पैदा होता है?

—राहुल देव

साक्षात्कार/अरुण शौरी

राजीव खुद अपनी सरकार उलटने में लगे हैं

पत्रकार होना कौन महान बात है—अरुण शौरी पूछते हैं। सवाल अजीब लग सकता है—इसलिए और भी ज्यादा, क्योंकि पूछनेवाले व्यक्ति ने पत्रकारिता में तहलका मचाकर काफी शोहरत हासिल की है। लेकिन अरुण शौरी पत्रकार की तुलना में जिहादी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को ज्यादा अहम मानते हैं। 'हम में से हरेक, नागरिक पहले—पेशेवर बाद में है,' वह कहते हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' के माध्यम से अरुण शौरी जब पहले-पहल उभरे थे, तो उन्होंने दोनों भूमिकाओं को बड़ी सफलता से एक दूसरे में मिला दिया था। थोड़े अंतराल के बाद अर्थशास्त्री से पत्रकार बने शौरी फिर अपनी पुरानी जगह पर हैं और सूचनाओं के विश्लेषण और उनकी चीर-फाड़ में लगे हैं। हाल के छापों के बाद रंजना कक्कड़ ने शौरी से बातें की हैं:

राजीव के प्रति पहले नरम रुख, लेकिन बाद में बदलने के संबंध में:

शौरी: मैं नहीं जानता, मुझे लोग कैसे राजीव के प्रति नरम रुख रखनेवालों में शुमार करते हैं। मैंने जो कुछ उनके बारे में कहा है, वह लिखित है। मैं उस समय नियमित रूप से लिख भी नहीं रहा था। पूना में आयोजित बाल स्मारक भाषणों में भी ऐसा कुछ नहीं था कि 'नरमी' दिखायी दे। हां, उनके सत्ता में आने से पहले मैंने यह कहा था कि वह किसी काम के नहीं—कि उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक साल बाद हरेक ने महसूस किया—और मैंने भी कि यह आदमी जैसी उम्मीद थी, उससे बेहतर निकला है।

मुस्लिम महिला विधेयक के मुद्दे पर एक बार उनसे रूबरू होने का मौका मिला था, तब मुझे लगा था कि वह छिछले, संवेदनहीन और झूठे हैं। वह कहते हैं कुछ, और करते हैं कुछ। अतः मेरे खयाल से यदि कोई एक उदाहरण दिया जा सकता है, तो वह १९८६ के मुस्लिम महिला विधेयक से संबंधित हो सकता है। उस समय मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वह आदमी नाजुक मसलों को भी गंभीरता से नहीं लेता।

छापा मारकर प्रेस को चेतावनी देना। उनके आने के बाद एक्सप्रेस के और कड़ा होने के बारे में:

शौरी: हां, लेकिन 'कड़ा' शब्द आपका है। मैं तो कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस खरी बात कहता है।

संपादकीय नजरिया बदलने के लिए दबाव (खासकर सरोज गोयनका की ओर से) डालने के संदर्भ में:

शौरी: जहां तक श्रीमती सरोज गोयनका का ताल्लुक है, उनकी ओर से मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला गया। न सरकार की ओर से और न गोयनका-परिवार की ओर से कुछ बदलने के लिए कभी फोन या बात की गयी। संपादकीय मामलों में मैं केवल रामनाथजी से संबंध रखता हूं।

इतने बड़े स्तर पर डाले गये छापों के कारणों के संबंध में:

शौरी: बिलकुल साफ है। 'इंडियन एक्सप्रेस' को उदाहरण बनाकर प्रेस को चेतावनी देना है।

'इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा फेरा का कथित उल्लंघन और उससे अखबार की विश्वसनीयता पर आंच आने के बारे में:

शौरी: मैंने खुद सुझाया था कि सभी अखबारों के खातों का सार्वजनिक आडिट हो। अब जो मसले उठाये जा रहे हैं, उनके बारे में आप मैनेजमेंट और गुरुमूर्ति से पूछें। मुझे हिसाब-किताब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात कहने की इजाजत जरूर चाहूंगा। जैसे अजिताभ बच्चन के खातों के कारण दूसरे लोगों के विदेशी खातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसी तरह अगर किसी अखबार ने कोई गलत काम किया है, तो पाठक को अंतर करना चाहिए। अधिकारी पूरे तथ्यों का पता लगाये और कानून के अनुसार अखबार को दंडित करें और इसी तरह बच्चन-बंधुओं के साथ पेश आना चाहिए। यह बात अखबार को याद रखनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत पाठक को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई अखबार कोई रोचक चीज उजागर करता है, तो उस रहस्योद्घाटन का महत्व इसलिए नहीं घट जाता कि स्वयं अखबार ने भी संपत्ति खरीदने के मामले में घपला किया है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं लगाये गये आरोपों से सहमत हूं। मेरा आशय दोनों बातों को स्पष्ट करना है।

छापों में बाधा डालने की बाबत:

शौरी: सवाल ही नहीं उठता। मैं और गुरुमूर्ति सुंदर नगर में रामनाथजी के साथ काफी पी रहे थे। जब वे लोग पहुंचे, तो हम यहां (आफिस में) नहीं थे। जब हम पहुंचे, तो हमने अफसरों से इतनी विनती की थी कि हमें 'सर्च वारंट' की प्रतिलिपि दे दें। पहले तो उन्होंने टालटूल की, फिर वे वारंट दिखाने के लिए राजी हो गये। तब उन्होंने किसी को फोन किया और कहा कि ये लोग वारंट की कापी मांग रहे हैं। छह-सात घंटों में हम केवल सरकारी अधिकारियों से अनुरोध करते रहे। जिन अधिकारियों को हमारे और आपके द्वारा दिये गये कर से वेतन मिलता है, उनसे अनुरोध करना क्या बाधा डालना है? दूसरी बात, उन्होंने अनेक पंचनामे तैयार किये। हरेक पंचनामे से यह जाहिर होता है कि छानबीन शांतिपूर्ण हुई और सभी ने सहयोग दिया। तीसरी बात, २०० सशस्त्र लोगों के साथ आये ३० प्रशिक्षित अधिकारियों को एक या दो लोग क्या बाधा पहुंचायेंगे? फिर मुश्किल से एक-दो बार मैं इधर-उधर गया हूंगा, बाकी पूरे समय तक मैं ५-६ पत्रकारों से घिरा रहा हूं—कभी-कभी तो यह तादाद ३० तक पहुंच जाती थी। उन्हीं की उपस्थिति में सारे फोन आये और मैंने सबके सामने बातें कीं। यही नहीं, उनके पास सात जगहों के लिए 'सर्च वारंट' थे, जिनमें से एक भी जगह भवन के इस हिस्से में नहीं है। दूसरे हिस्से में कार्यरत लोगों को मैं इस हिस्से में बैठा हुआ कैसे रोक सकता हूं?

छापों की पूर्व सूचना के मुतल्लिक:

शौरी: इस बार नहीं।

राजीव गांधी को छापों के बारे में जानकारी न होने के संदर्भ में:

शौरी: बिलकुल बकवास। हमने संपादकीय लिखा था—'एनफ टू मेक ए हार्स लाफ'। वी०पी० सिंह पर इलजाम लगा है कि उन्होंने बिना प्रधानमंत्री को सूचित किये जांच का आदेश दे दिया। प्रधानमंत्री को इस तरह का विकेन्द्रीकरण सहन नहीं है। जिस अखबार के ग्यारह संस्करण हों और उस पर छापा पड़े और प्रधानमंत्री को पता न हो—यह कैसे हो सकता है। खासकर उस लड़ाई की, जिसे वह अपने साथ मानते हैं।

अखबार के वर्तमान नरम रुख के संबंध में:

शौरी: मेरे नजर में यह गलत धारणा है। हमारे संपादकीय देखिए, हर सप्ताह तो कोई

बड़ा मामला हो नहीं सकता। राजीव गांधी जो कुछ संसद में कहते थे, हम उसी को आधार बनाते थे। लेकिन अब संसद का सत्र नहीं चल रहा, इसलिए रोजाना हमें बड़े मामले नहीं मिल सकते। क्या रवि शंकर के कार्टूनों में कम पैनापन है?

एक्सप्रेस के बढ़ते प्रसार के बारे में:
शौरी: समझ में नहीं आता कि राजीव गांधी के इस अहसान को कैसे चुकायें क्या हमें उन्हें वेतन देना चाहिए? या उसी तरह का परामर्श शुक्ल दिया जाये जैसा विन चड्ढा को दिया गया है? या अनुबंध निरस्त होने तक इंतजार करें और फिर समापन राशि दी जाये? हम धर्मसंकट में फंसे हैं।

राजीव के भविष्य के संबंध में:
शौरी: अगर सुधरेंगे, रहेंगे, देश का भला होगा। नहीं सुधरेंगे, जायेंगे, देश का भला होगा।

छापों का ज्यादातर अखबारों की 'चुप्पी' के संदर्भ में:
शौरी: मैं मानता हूं, मैं अखबारों का अच्छा पाठक नहीं हूं। इसलिए मुझ पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं, उसका पहले से पता होता है। एक संपादक दोस्त ने मुझे बताया कि एक मालिक ने इस विषय पर 'संतुलित' संपादकीय तक लिखने से रोकने के लिए भरसक कोशिश की। श्री अडवाणी का यह जायजा ठीक ही है कि इन लोगों को जब झुकने के लिए कहा जाता है, तो ये घुटनों के बल रेंगना शुरू कर देते हैं।

राजीव का तख्ता पलटने में लगी एक्सप्रेस-गोयनका-शौरी की तिकड़ी के बारे में:
शौरी: मैं यह सोचने की गुस्ताखी नहीं कर सकता कि मैं सरकार को उलट सकता हूं। या कोई एक अखबार सरकार को पलट सकता है। हां, एक व्यक्ति जरूर पूरी ताकत से सरकार को उलटने में लगा है—वह हैं, राजीव गांधी। ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरता जब वह अपनी सरकार को मिटाने का कोई-न-कोई काम न करते हों।

जेठमलानी और गुरुमूर्ति के साथ गोयनका पर संपादकीय रुख को सख्त बनाने के बारे में:
शौरी: यदि कोई यह सोचता है कि मात्र 'संपादकीय रुख' के कारण सारी परिसंपत्ति को छोड़ने के लिए गोयनका पर दबाव डाला जा रहा है, तो वह मूर्ख है। रामनाथजी एक दृढ़ इच्छावाले व्यक्ति हैं। वैसे भी क्या यह संपादकीय नीतियां बनाने और अखबार चलाने का रास्ता है? रामनाथजी छपने से पहले कभी अखबार नहीं देखते। छापों के दिन रामनाथजी घर पर थे, गुरुमूर्ति वकीलों से परामर्श में लगे थे और मैं प्रेस के लोगों से घिरा था। जो संपादकीय दूसरे दिन छपकर आया, उसे मैंने समय मिलने पर आधे घंटे में डिक्टेट करवाया था।

एक्सप्रेस इसका पर्दाफाश करेगा। अमिताभ बच्चन के खिलाफ प्रकाशित दस्तावेज यद्यपि राम जेठमलानी द्वारा जुटाया गया था, किंतु कहा जाता है कि इसका खर्च (जो काफी अधिक माना जाता है) रामनाथ गोयनका ने ही वहन किया था। इसीलिए यह आरोप सरकार निरंतर लगाती रही है कि एक्सप्रेस उसे बेदखल करना चाहता है, यद्यपि अरुण शौरी इससे असहमत हैं, ''सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करना हमारा ध्येय है, गिराना या बनाना नहीं।''

बात कुछ भी हो, यह आम राय है कि प्रेस का आक्रामक रुख, विशेषकर एक्सप्रेस का, सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। खास तौर से जबकि एक्सप्रेस समूह ने न केवल बोफोर्स, पनडुब्बी व बच्चन बंधुओं के विवादों का ठेका ले रखा है, बल्कि राजीव सरकार के लिए चुनौती बने विश्वनाथ प्रताप सिंह के पूरे अभियान को भी वह पूरी ताकत के साथ धुआंधार समर्थन दे रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद से दो संवाददाता लगभग दिन भर उनके निवास पर नियुक्त कर दिये गये हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस समूह के संवाददाताओं की एक टीम सदैव इसके लिए तैयार रहती है कि जब कभी सिंह बाहर दौरे पर जायें, तो उनके कार्यक्रमों को खास अहमियत के साथ विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जा सके। रामनाथ गोयनका ने यही शैली श्रीमती गांधी के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को बल देने के लिए अपनायी थी। जे०पी० के बाद अब वी०पी० सिंह के आंदोलन को एक्सप्रेस द्वारा खुला समर्थन देने से सरकारी सूत्रों के इस मत को और बल मिला कि वी०पी० सिंह, रामनाथ गोयनका, नस्ली वाडिया, जेठमलानी, गुरुमूर्ति आदि के मध्य एक लंबे अरसे से मजबूत गठबंधन व तालमेल बना हुआ है। कल्पनाथ राय सहित अनेक कांग्रेसी सांसद लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वित्त तथा रक्षा मंत्रालय की गोपनीय फाइलों से महत्वपूर्ण सूचनाएं एक्सप्रेस समूह को दी हैं, जिनके आधार पर एक्सप्रेस एक-के बाद-एक राजीव-विरोधी खबरें छापता रहा है। एक्सप्रेस पर छापा मारकर सरकार अपने राजनीतिक शत्रु वी०पी० सिंह को न केवल कमजोर करना चाहती थी, बल्कि वह यह भी चाहती थी कि एक्सप्रेस पर छापों के दौरान कोई ऐसा दस्तावेज मिल जाये जो वी०पी० सिंह नस्ली वाडिया तथा फेयरफैक्स के रिश्तों के सबूत के रूप में पेश किया जा सके। एक्सप्रेस के साथ उसी दिन नस्ली वाडिया के दो अधिकारियों के घर पड़े छापे में भी अधिकारियों को ऐसे ही किसी 'कागज' की तलाश थी।

रणनीति: इसके पीछे रणनीति बनी थी कि यदि प्रेस पर समुचित नियंत्रण पा लिया जाये और प्रेस को अविश्वसनीय बना दिया जाये, तो रोडरोलर बहुमत की राजीव सरकार के ऊपर से विपत्ति के बादल अनायास ही छंट जायेंगे। इसी कारण लोगों को विश्वास हो गया है कि रामनाथ गोयनका के साथ छिड़ी इस लड़ाई का संचालन स्वयं राजीव की देखरेख में हो रहा है। क्योंकि इस लड़ाई के नतीजे पर उनका भविष्य जो टिका है!

आरोप बेबुनियाद: अरुण जैतली

रामनाथजी योद्धा हैं: प्रभाष जोशी

एक परिणाम बिलकुल इसके विपरीत भी हो सकता है—यदि 'इंडियन एक्सप्रेस' अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह झूठा सिद्ध करने में सफल हो जाये। यदि ऐसा हो गया (संभावना यद्यपि धूमिल है, क्योंकि एक्सप्रेस एक व्यापारिक संस्थान तो है ही और यदि सरकार हाथ धोकर, दूरबीन लेकर, पीछे पड़ी ही रही तो, कहीं-न-कहीं किसी छोटे-बड़े मामले में पकड़ ही लेगी), तो वह राजीव-सरकार को विनाश के और निकट ले जायेगा। सफलता के हर्ष में एक्सप्रेस की आवाज तो बुलंद होगी ही, समस्त भारतीय प्रेस को आक्रमण करने का सुंदर

आरोप-प्रत्यारोप

एक्सप्रेस पर छापा पड़ते ही राजस्व खुफिया निदेशालय ने इतने कानूनों को तोड़ा है तो निश्चित रूप से वह परेशानी में पड़ सकता है। एक ओर राजस्व खुफिया निदेशालय आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और एक्सप्रेस के लिए बच निकलना कठिन है। दूसरी ओर एक्सप्रेस परिवार मूछों पर ताव दिये घूम रहा है क्योंकि उसका दावा है कि उसके खिलाफ छापे में कुछ मिला ही नहीं है। एक बातचीत के दौरान श्री एस० गुरुमूर्ति (एक्सप्रेस के कानूनी सलाहकार) ने बताया कि इमरजेंसी के समय से आज तक उनका केवल एक ही विशेष काम रहा है-वह यह कि "एक्सप्रेस को कानून के माकूल दायरे में ही रखा जाये। अतः कानून उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसा ही है, तो सरकार हमारे ऊपर दावा क्यों नहीं करती?" सरकार से लोहा लेने के लिए एक्सप्रेस कितना तत्पर है यह इसी बात से जाहिर हो जाता है कि यद्यपि कई लोगों ने अंतरिम जमानत ले ली है किंतु रामनाथ गोयनका, गुरुमूर्ति व अरुण शौरी ने जानबूझकर नहीं ली है। वे जेल जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं।

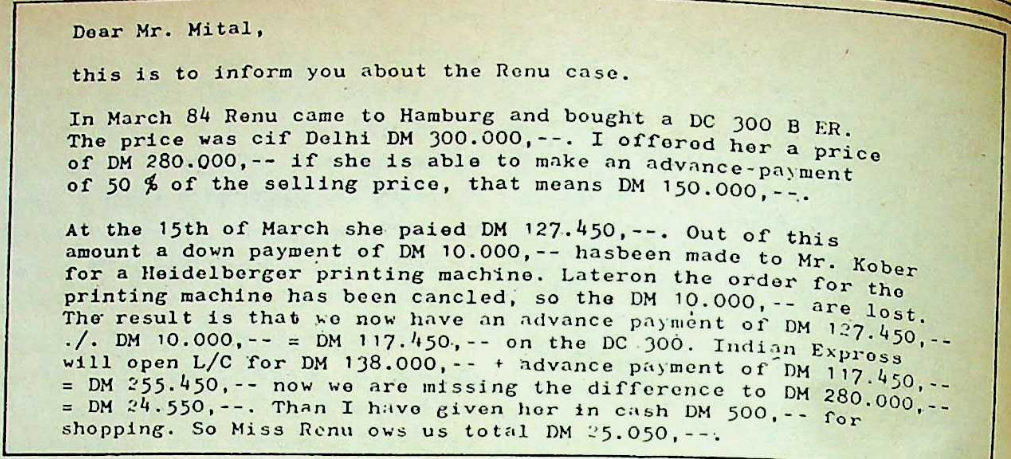

Dear Mr. Mital,

this is to inform you about the Renu case.

In March 84 Renu came to Hamburg and bought a DC 300 B ER. The price was cif Delhi DM 300.000,--. I offered her a price of DM 280.000,-- if she is able to make an advance-payment of 50 % of the selling price, that means DM 150.000,--.

At the 15th of March she paied DM 127.450,--. Out of this amount a down payment of DM 10.000,-- hasbeen made to Mr. Kober for a Heidelberger printing machine. Lateron the order for the printing machine has been cancled, so the DM 10.000,-- are lost. The result is that we now have an advance payment of DM 127.450,-- ./. DM 10.000,-- = DM 117.450,-- on the DC 300. Indian Express will open L/C for DM 138.000,-- + advance payment of DM 117.450,-- = DM 255.450,-- now we are missing the difference to DM 280.000,-- = DM 24.550,--. Than I have given her in cash DM 500,-- for shopping. So Miss Renu ows us total DM 25.050,--.

दस्तावेज 'ए' : हेम्बर्ग फर्म द्वारा अपने दिल्ली प्रतिनिधि आर०पी० मित्तल को लिखा गया पत्र

तमाम आरोपों की जांच से दो-तीन आरोप ही कुछ बड़े और ठोस जान पड़ते हैं। सबसे प्रथम है एक्सप्रेस द्वारा हांगहुआ मशीनों की खरीद। निदेशालय का कहना है कि इन मशीनों को ३० हजार कापी प्रति घंटा छापने वाली कहकर एक्सप्रेस ने इन पर कम ड्यूटी दी है क्योंकि वास्तव में यह केवल २०-२२ हजार कापी ही छाप रही है। इन्हीं मशीनों की बाबत दूसरा आरोप ये है कि ये बड़ौदा, राजकोट और अहमदाबाद के लिए आयात की गयी थीं किंतु लगायी हैदराबाद और बंगलौर में गयीं, जो कानूनी उल्लंघन है।

एक्सप्रेस केस बयान करते हुए राम जेठमलानी के सहयोगी अरुण जैतली ने बताया कि दोनों ही आरोप बेकार और थोथे हैं। उनका कहना है कि एक्सप्रेस नें पूरी मशीन न लेकर एक भाग ही लिया है, जिसका अभी तक पूरी तरह पुरानी मशीनों से तालमेल नहीं बैठा है, यद्यपि प्रयास जारी है। इसी कारण एक्सप्रेस ने अभी पूरा भुगतान भी नहीं किया है। अरुण जैतली ने निदेशालय पर आरोप लगाते हुए बताया कि टाइम्स आफ इंडिया सहित अन्य १० संस्थानों ने भी इन्हीं मशीनों को खरीदा है, और उन्हें भी इसी समस्या का सामना करना

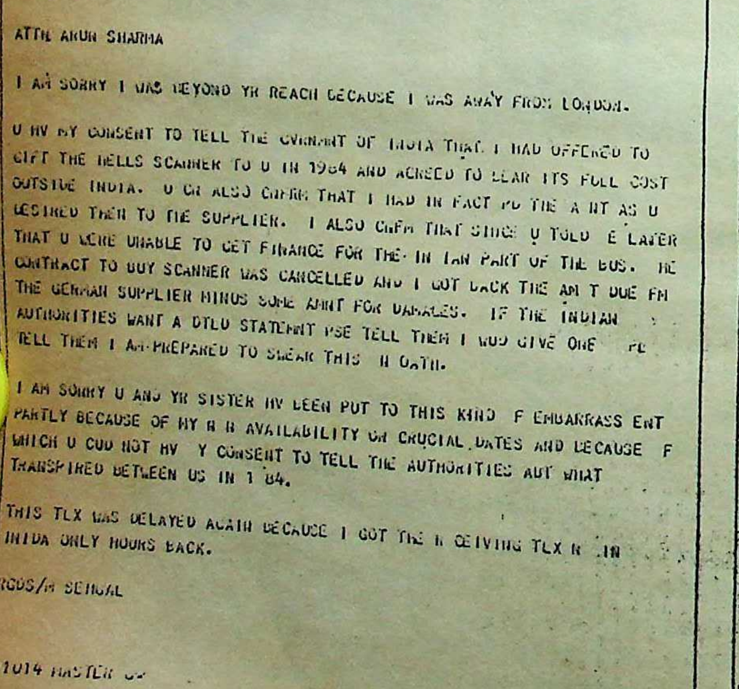

```
91014 MASTER G

14.9.87

ATTN ARUN SHARMA

I AM SORRY I WAS BEYOND YR REACH BECAUSE I WAS AWAY FROM LONDON.

U HV MY CONSENT TO TELL THE GVRNMNT OF INDIA THAT I HAD OFFERED TO
GIFT THE HELLS SCANNER TO U IN 1984 AND AGREED TO BEAR ITS FULL COST
OUTSIDE INDIA.  U CN ALSO CNFRM THAT I HAD IN FACT PD THE A NT AS U
DESIRED THEM TO THE SUPPLIER.  I ALSO CNFM THAT SINCE U TOLD  E LATER
THAT U WERE UNABLE TO GET FINANCE FOR THE IN IAN PART OF THE BUS.  HE
CONTRACT TO BUY SCANNER WAS CANCELLED AND I GOT BACK THE AM T DUE FM
THE GERMAN SUPPLIER MINUS SOME AMNT FOR DAMAGES.  IF THE INDIAN
AUTHORITIES WANT A DTLD STATEMNT PSE TELL THEM I WUD GIVE ONE    PL
TELL THEM I AM PREPARED TO SWEAR THIS  N OATH.

I AM SORRY U AND YR SISTER HV BEEN PUT TO THIS KIND  F EMBARRASS ENT
PARTLY BECAUSE OF MY N N AVAILABILITY ON CRUCIAL DATES AND BECAUSE  F
WHICH U CUD NOT HV  Y CONSENT TO TELL THE AUTHORITIES ABT WHAT
TRANSPIRED BETWEEN US IN 1 84.

THIS TLX WAS DELAYED AGAIN BECAUSE I GOT THE R CEIVING TLX N  .IN
INIDA ONLY HOURS BACK.

RGDS/M SEHGAL

91014 MASTER G
```

दस्तावेज 'बी' :मुकेश सहगल द्वारा अरुण शर्मा को भेजा गया टेलेक्स संदेश

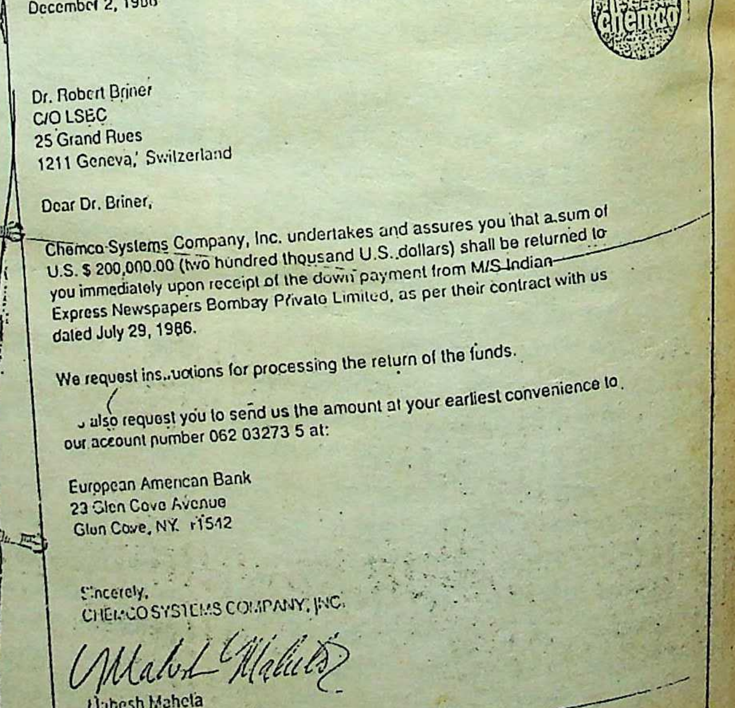

CO SYSTEMS COMPANY, INC. - HERB HILL ROAD • GLEN COVE, N.Y. 11542
Subsidiary of Powers Chemco, Inc. 516 676-1000

B 8/ir
1988

December 2, 1986

Dr. Robert Briner
C/O LSBC
25 Grand Rues
1211 Geneva, Switzerland

Dear Dr. Briner,

Chemco Systems Company, Inc. undertakes and assures you that a sum of U.S. $ 200,000.00 (two hundred thousand U.S. dollars) shall be returned to you immediately upon receipt of the down payment from M/S Indian Express Newspapers Bombay Private Limited, as per their contract with us dated July 29, 1986.

We request instructions for processing the return of the funds.

also request you to send us the amount at your earliest convenience to our account number 062 03273 5 at:

European American Bank
23 Glen Cove Avenue
Glen Cove, NY. 11542

Sincerely,
CHEMCO SYSTEMS COMPANY, INC.

Mahesh Mahela

Mahesh Mahela
Assistant to the President

दस्तावेज 'सी' : महेश मेहता द्वारा ब्राइनर को लिखा गया पत्र

पड़ रहा है, किंतु उनको निदेशालय ने अछूता छोड़ दिया है। यही नहीं एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस पहले ही मिला था और कुछ ड्यूटी देकर, कुछ वापस लेकर मामला ठीक कर लिया गया था।" यह तो पूरा अध्याय ही समाप्त हो चुका है। इसे फिर से उठाने-उभारने का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

एक्सप्रेस ग्रुप के विरुद्ध दूसरा आरोप यह है कि उसने सन १९८४ में हैम्बर्ग (पश्चिम जर्मनी) में स्थित 'डाईट्रिच कुहने' फर्म से हैल नामक स्कैनर आयातित करने के लिए कम-बीजक प्रस्तुत किया। इस मशीन की कीमत १,३८,००० मार्क (एक मार्क ७.१५ रुपये का बराबर होता है) बतायी गयी। परंतु हैम्बर्ग की फर्म के दिल्ली प्रतिनिधि आर॰पी॰ मित्तल के यहां से जो लिखित प्रमाण (देखें दस्तावेज 'ए') मिला है, उससे यह साफ पता चलता है कि स्कैनर की असली कीमत २,८०,००० मार्क थी। इस तरह कुल मिलाकर ४.५ लाख रुपयों के सीमा-शुल्क की चोरी की गयी। दिलचस्प बात यह है कि स्कैनर की इस खरीद से रामनाथ गोयनका की निजी सचिव रेणु शर्मा भी काफी करीबी तौर पर संबंधित थीं। सभी पक्षों को देखते हुए डी॰आर॰आई॰ का यह विश्वास है कि गोयनका के पास विदेश में धन है।

डी॰आर॰आई॰ के अनुसार यद्यपि स्कैनर का वास्तविक मूल्य २,८०,००० मार्क था, लेकिन एक्सप्रेस ग्रुप ने सीमा कर बचाने के लिए केवल १,३८,००० मार्क के लिए ही साख-प्रपत्र खोला। रेणु शर्मा को जिनेवा भेजा गया। उसे यह हिदायत दी गयी कि वह वहां से १,४२,००० मार्क लेकर हैम्बर्ग में कुहने को वह यह रकम दे और स्कैनर को खरीदे जाने का सौदा पक्का करे। परंतु, रेणु ने मौके का फायदा उठाया। यह पता चलता है कि रेणु शर्मा ने कुहने को अग्रिम राशि के रूप में केवल १,१७,४५० मार्क ही दिया। इस रकम में से भी १०,००० मार्क रेणु शर्मा के भाई अरुण शर्मा के द्वारा एक 'हाइडिल बर्ग प्रिंटिग मशीन' खरीदने के लिए अग्रिम राशि के रूप में कुहने को दिया गया। (बाद में अरुण शर्मा ने यह मशीन नहीं खरीदी और १०,००० मार्क की यह अग्रिम राशि जुर्माने के तौर पर जब्त कर ली गयी)। बाकी १५,००० मार्क अमरीका की यात्रा के लिए रख लिया गया।

इस तरह कुल मिलाकर कुहने को एक्सप्रेस ग्रुप को स्कैनर मशीन सप्लाई करने के लिए केवल १,१७,४५० मार्क ही मिला। कुहने ने उस समय तक के लिए मशीन भेजने से इनकार कर दिया, जब तक बाकी २५,००० मार्क का भुगतान उसको न मिल जाये (देखें दस्तावेज 'ए') रेणु शर्मा की इस हरकत का पता जब गोयनका को चला, तो उन्होंने उसे नौकरी से तुरंत निलंबित कर दिया।

इसके उत्तर में रेणु और अरुण शर्मा का यह कहना है कि २,८०,००० मार्क दो स्कैनर मशीनों का मूल्य था न कि एक मशीन का, क्योंकि एक मशीन वह स्वयं अपने लिए भी खरीदना चाहते थे।

कुहने को २५,००० मार्क कम दिये जाने के बारे में अरुण शर्मा का कहना है कि यह रकम उन्हें प्राप्त होने वाला कमीशन था जो प्रस्तावित दो स्कैनरों और एक हाइडिल बर्ग मशीन की खरीद पर उन्हें मिलना था। वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन रेणु के माध्यम से इस बात की व्यवस्था की थी कि भारत में इन मशीनों के आने पर गोयनका सीमा—कर की अदायगी करके उसकी मदद करेंगे। बाद में अरुण शर्मा ने अपने लिए एक स्कैनर और एक हाइडिल बर्ग प्रिंटिग मशीन खरीदने का इरादा बदल दिया था।

आगे स्पष्टीकरण देते हुए अरुण शर्मा कहते हैं कि वह स्वंय जो मशीन खरीदना चाहते थे, उसके लिए अपने निकटतम मित्र मुकेश सहगल से १,५०,००० मार्क मिला था जो उन्होंने बाद में वापस कर दिया (देखें दस्तावेज 'बी')।

निदेशालय के विचार में दूसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केस डा॰ ब्राइनर से संबंधित है। अरुण जैतली ने बताया कि एक्सप्रेस एक 'फेवरमैन सिस्टम' ८ करोड़ की लागत से खरीद रहा था। आर्डर के अनुसार एक्सप्रेस को अप्रैल, '८६ तक एक एल॰सी॰ (साख्प्रपत्र) खोलनी थी। चूंकि सरकारी लाइसेंस में देर थी, इसलिए आर्डर रद्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। फेवरमैन सिस्टम फर्म आर्डर इस शर्त पर जारी रखने को तैयार हुई कि कोई दो लाख डालर की गारंटी भरे। रामनाथ गोयनंका ने अपने मित्र डा॰ राबर्ट ब्राइनर, जो एक जज हैं, से कैमको कंपनी से बात करने को कहा। विवेक खैतान के कार्यालय से बराबद एक पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। यह पत्र न्यूयार्क स्थित कैमको सिस्टम्स कंपनी के महेश मेहता ने ब्राइनर को लिखा था (देखें दस्तावेज 'सी')। तदनुसार डा॰ ब्राइनर ने २ लाख डालर देकर गारंटी भरी। यह स्पष्ट कहा गया था कि एक्सप्रेस की एल॰सी॰ खुलने के पश्चात यह रकम डा॰ ब्राइनर को वापस चली जायेगी। निदेशालय यह सिद्ध करने पर तुला है कि एक्सप्रेस के पास विदेश में पैसा है और ब्राइनर द्वारा २ लाख की रकम उसी मे से दी गयी है। बाद में निदेशालय कह रहा है कि यह यदि कानूनी उल्लंघन नहीं भी हो तो तकनीकी उल्लंघन तो है ही।

—रंजना कक्कड़

अवसर भी मिल जायेगा। यह आक्रमण निश्चित रूप से राजीव-सरकार के जीर्ण-शीर्ण भवन को चरमरा कर रख देगा। अतः गोयनका के लिए यह लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी राजीव के लिए। यदि वह जीतने में सफल हो गये, तो उनके संपूर्ण जीवन का संघर्ष सफल हो जायेगा और भारतीय प्रेस के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। किंतु यदि वह विफल हुए, तो उनकी हार प्रेस के पैरों में ऐसी बेड़ियां डलवा देगी, जिनसे पीछा छुड़ाना अत्यंत दुष्कर होगा। सरकार को किसी भी समाचार संस्थान पर धावा बोलने के लिए बहाना मिल जायेगा और प्रेस की विश्वसनीयता मिट्टी में मिल जायेगी। भारतीय प्रेस की विदेशी प्रेस-जगत में बड़ी इज्जत है।यदि एक्सप्रेस की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आयी, तो विदेशों में भी भारतीय प्रेस की इज्जत पर बट्टा लग जायेगा।

परिणाम दोनों के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका अनुमान दोनों को है। दोनों को शायद यह भी समझ में आने लगा है कि एक दूसरे को समाप्त करने, नीचा दिखाने के परिणाम से विजेता भी अछूता नहीं रहेगा। उसकी साख पर भी कुछ आंच निश्चित रूप से आयेगी। शायद इसी कारण दोनों खेमों में जोश होते हुए भी एक्सप्रेस पर पड़े छापों के दो सप्ताह बाद दोनों प्रतिद्वंद्वियों के हाथ कुछ थमे से दिखायी पड़ने लगे हैं।

हालांकि रामनाथ गोयनका व उनकी पुत्रवधू सरोज गोयनका को राजस्व खुफिया निदेशालय, मद्रास ने पूछताछ के लिए दो बार बुलाया है, किंतु दो सप्ताह के भीतर आरोप पत्र जमा करने की कार्यवाही अभी नहीं की है। फिर भी रामनाथ गोयनका से की गयी पूछताछ के विषय में एक्सप्रेस में अत्यधिक रोष है—गुरुमूर्ति कहते हैं, "एक मामूली से केस के लिए ८५ वर्षीय रामनाथ गोयनका को निदेशालय के दफ्तर में घसीटना, परेशान करने के सिवा और क्या है? सरकार इससे अधिक घृणित हरकत और क्या कर सकती थी?" लेकिन वह भूल रहे हैं कि इससे ज्यादा बुरा सलूक ८५ वर्षीय एस॰एल॰ किर्लोस्कर के साथ पूना में हुआ था, जबकि उस समय वी॰पी॰ सिंह वित्तमंत्री थे।

फिर भी बदले हुए रवैयों के कारण अटकल लगायी जाने लगीं है कि पिछली बार (इमरजेंसी के बाद) की तरह इस बार भी किसी समझौते का समस्या को सुलझाने में उपयोग किया जायेगा। मसलन सरकार एक्सप्रेस को कोर्ट-कचहरी-जेल में नहीं घसीटेगी और एक्सप्रेस अपने आक्रामक रूप को अलविदा कहेगा।

यदि ऐसा हुआ, तो गोयनका के सेनापति अरुण शौरी का क्या हश्र होगा? क्या पिछली बार के समझौते की तरह इस बार भी उनकी बलि चढ़ेगी? इस विषय पर गुरुमूर्ति से बात हुई, तो वह आगबबूला हो गये। समझौते की चर्चा को सरकारी प्रचार करार देते हुए उन्होंने कहा, "असंभव है। समझौते का सवाल ही नहीं उठता। जिस लड़ाई के जिन मुद्दों के लिए इंडियन एक्सप्रेस का जन्म

किस्सा रेणु शर्मा का

गोयनका के साथ रेणु शर्मा (बायें)

“रेणु शर्मा रामनाथ गोयनका के इतने नजदीक थीं कि डा० ब्राइनर से जिनेवा में २ लाख ड्यूश मार्क लेकर डाइट्चि कुहने को पहुंचाने का काम उनको सौंपा गया था—उन्होंने ही यह पैसा हाबुर्ग पहुंचाया था।”

“रेणु शर्मा अत्यन्त चतुर और महत्वाकांक्षी महिला हैं। एक्सप्रेस छोड़ने पर, बदला लेने के लिए वह रिलायंस से जा मिलीं और एक्सप्रेस का भंडाफोड़ किया। किंतु अब एकाएक कारण कुछ भी हो, फिर पलट कर एक्सप्रेस से जा मिली हैं और एक बार फिर पाला बदल रही हैं।”

यदि ऊपर दिये गये आरोपों में लेशमात्र भी सचाई है, तो सर गंगाराम अस्पताल के कमरा नंबर ५०१ से निकली गुलाबी सलवार सूट में सजी युवती रेणु शर्मा, एक कुशल अभिनेत्री भी हैं। वैसे भी इंडियन एक्सप्रेस पर राजस्व खुफिया निदेशालय के जबर्दस्त छापों के बाद तेज हुए घटनाक्रम में रेणु शर्मा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण व जटिल रही है। आरोपों और अफवाहों का बाजार गरम रहा है और इनके बीच रेणु शर्मा एक पहेली बन कर रह गयी हैं।

पहेली को सुलझाने के लिए जब रेणु शर्मा की खोज आरंभ की, तो कहीं भी उनका अता-पता न था। एक्सप्रेस में यदि किसी के सामने उनका नाम भी लिया गया, तो वह जवाब देने से कतरा गया। राजस्व खुफिया निदेशालय के प्रवक्ताओं ने सूचना दी कि एक्सप्रेस उन पर बेहिसाब दबाव डालने के प्रयास में है, इसी कारण वह भूमिगत हो गयी हैं। खोज जारी रही, अंत में अस्पताल के उस कमरे के नंबर की सूचना मिल ही गयी जहां रेणु शर्मा अपनी बीमार मां की तीमारदारी में वयस्त थीं।

मिलते ही रेणु शर्मा ने दो-तीन बातों का खुलासा किया। एक तो यह कि वह पत्रकारों और अखबारों की सुर्खियों से दूर रहना चाहती हैं। इस संवाददाता से मिलने का निश्चय उन्होंने इसलिए किया है कि तमाम अफवाहों को समाप्त कर सकें।

दूसरी बात यह कही कि न तो वह अंडरग्राउंड (भूमिगत) हैं—“आखिर आप मुझसे मिल ही रही हैं”—न ही इंडियन एक्सप्रेस ने उन पर किसी प्रकार का दबाव डाला है, जिसके कारण वह ऐसा कुछ करने को मजबूर हो जायें। हां छापे के दिन की घटनाओं से वह अवश्य घबरा गयी थीं—उनसे बचने और हिम्मत बटोरने के लिए उन्होंने अगले तीन-चार दिन अपनी किसी सहेली के यहां बिताये थे। “मेरी मानसिक हालत ऐसी थी कि फोन की या दरवाजे की घंटी बजती, तो मैं यह सोचकर कि डीआरआई वाले फिर न आ गये हों, पसीने-पसीने हो जाती थी। अब मैंने अपने को काफी संभाल लिया है, मन को ढाढ़स दिया है कि जब कर नहीं, तो डर कैसा।”

एक्सप्रेस के अपने संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि १९७९ से १९८३ तक वह इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका की निजी सचिव के पद पर काम करती रहीं। १९८३ के अंत में जब उनका तबादला बंबई कर दिया गया, तो उन्होंने लंबी छुट्टी ले ली और उसके बाद कभी वापस नहीं गयीं। “मेरा परिवार दिल्ली में है। मेरे लिए बंबई जाकर अकेले रहना असंभव था।” एक्सप्रेस छोड़ने के उपरान्त वह अपने पिता के व्यवसाय में हाथ-बंटाती रहीं और १९८६ में वह एक आई०पी०एस० अधिकारी के साथ विवाह हो जाने पर अरुणांचल प्रदेश चली गयीं।

वहीं से वह अगस्त के अंत में अपनी बीमार मां को देखने आयी हैं। एक सितंबर को ही उनके घर पर अनायास छापा पड़ा। “जब डीआरआई के ७ अधिकारी हमारे घर सुबह ९ बजे पहुंचे, तो शुरू में हम लोगों को समझ ही नहीं पड़ा कि वे कौन हैं और क्यों आये हैं? वह एक के बाद एक कागज देखते रहे—ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ विशेष कागजों की तलाश थी। जब उन्होंने मेरे एक्सप्रेस के नियुक्ति पत्र आदि को कब्जे में ले लिया, तो समझ में आया कि यह छापा क्यों डाला गया है।”

श्रीमती रेणु शर्मा का कहना है कि यद्यपि अधिकांश अधिकारियों का व्यवहार अच्छा था, किंतु कुछ जूनियर अधिकारियों का व्यवहार—उनके घर और बाद में निदेशालय के दफ्तर में रूखा और बदतमीजी का था। डीआरआई के कथन, कि उन्होंने और उनके भाई ने स्वेच्छा से निदेशालय के दफ्तर जाकर एक्सप्रेस के विरुद्ध गवाही दी, से रेणु पूर्णतया असहमत हैं।” स्वेच्छा से जाने का सवाल ही नहीं है। छापे के दौरान अधिकारी बारी-बारी से फुसलाने-धमकाने का काम करते रहे। मैं लगातार जानकारी से इनकार करती रही। फिर हारकर राजी हुई।” पूछताछ के लिए उनके भाई को भी साथ लिया गया था। निदेशालय के दफ्तर में दोनों को अलग-अलग कमरों में रखा गया और फुसलाने-धमकाने का सिलसिला जारी रहा। “मुझ पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि मैं एक्सप्रेस के विरुद्ध कुछ लिखूं-चाहे एक लाइन ही। कभी कहा गया कि मेरे भाई ने सब कुछ कबूल कर लिया है, कभी यह कि स्वयं रामनाथजी ने कहा कि मैंने डा० ब्राइनर से पैसे लिये थे। अत्यन्त बदहवास मानसिक हालत में मैंने उस लेख की हूबहू कापी कर दी जो मेरे समक्ष रख दिया गया था। किंतु उस पर हस्ताक्षर करने से पहले ही मेरे हाथ रुक गये। उनसे वायदा कर कि कल उस पर हस्ताक्षर करूंगी, मैं बड़ी कठिनाई से घर वापस आयी।”

अगले दिन सुबह ही डीआरआई के नाम एक पत्र लिखकर रेणु शर्मा ने उसे नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पोस्ट किया और अपनी सहेली के घर जा छुपीं। बाद में, उनका हाल जानने आये अरुण शौरी को उनकी मां ने पत्र की एक प्रतिलिपि दे दी। यही प्रतिलिपि बाद में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई।

अपने ऊपर लगाये आरोपों पर बातचीत करते हुए श्रीमती शर्मा ने बताया कि उन्होंने आज तक कभी डा० ब्राइनर को देखा भी नहीं है। “श्रीमती ब्राइनर, जब रामनाथजी की पौत्री कविता के विवाह में शामिल होने आयी थीं, तो उनका हवाई-अड्डे पर स्वागत करने व बाद में विदा करने का काम मुझे सौंपा गया था, इसलिए उनसे मेरी मुलाकात अवश्य है।” सचाई क्या है, कब और कैसे सामने आयेगी, कहा नहीं जा सकता। किंतु क्या उसके लिए किसी परिवार को मानसिक यंत्रणा देने का हक बनता है? अस्पताल के दो कमरों की ओर इशारा करते हुए रेणु शर्मा ने दुखी स्वर में कहा— “एक में मेरी मां है, दूसरे में मेरा भाई। डीआरआई को क्या हक है कि इतना तनाव फैलायें कि मेरे परिवार का यह हाल हो जाये।”

—रंजना कक्कड़

हुआ था, उनके लिए वह समझौता करने की जगह, मरना, समाप्त हो जाना अधिक पसंद करेगा।''

अधिकार और सीमाएं: समस्त आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच एक मूल प्रश्न जो उभर कर आता है, वह है अधिकारों की सीमाएं। निश्चित रूप से प्रेस और सरकार दोनों के लिए इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सीमा लांघते ही अधिकार, अधिकार न रहकर खुली छूट बन जाते हैं। गोयनका-राजीव संघर्ष के संदर्भ में दोनों तरफ से यही आरोप लग रहे हैं कि दूसरे ने अपने अधिकारों की सीमा लांघ कर कानून का उल्लंघन किया है। एक्सप्रेस की पत्रकारिता की आलोचना करते हुए 'टेलीग्राफ' के संपादक एम०जे० अकबर कहते है, ''खोजी पत्रकारिता और दोषारोपण केंद्रित पत्रकारिता में अंतर है।'' और यह अंतर अकबर की दृष्टि में एक्सप्रेस बनाये न रख सका है। उनके इस विचार से ''कि समाचार पत्रों को समाचार छापने की आजादी है, नोट छापने की नहीं'', एक्सप्रेस के एस० गुरुमूर्ति पूर्णतया सहमत हैं और कहते हैं, ''अगर इंडियन एक्सप्रेस को पैसे ही बनाने होते, तो वह विपक्ष के खेमे में न होकर औरों की तरह पैसा बनाने वाले गिरोह के साथ होता।'' मतलब सारा साफ है।

प्रेस और सरकार के इन्हीं अधिकार-सीमाओं की विवेचना करते हुए 'स्टेट्समैन' के पूर्व संपादक एस० सहाय का कहना है, ''इस देश का शासन कम-से-कम अभी तक कानून द्वारा संचालित है। जिस तरह कोई यह दावा नहीं कर सकता कि प्रेस कानून के ऊपर है, उसी तरह यह तर्क भी नहीं दिया जा सकता कि प्रेस द्वारा कानून के किसी उल्लंघन को, दूसरों की तुलना में, छूट मिलनी चाहिए। इसी प्रकार कोई यह दावा नहीं कर सकता कि चूंकि सरकार के पास सत्ता और कार्यान्वियन तंत्र है, इसलिए वह अपने विरोधियों के खिलाफ इसका दुरुपयोग करने को स्वतंत्र है।''

सरकार के मुखिया और एक भीमकाय समाचार प्रतिष्ठान के मालिक के बीच छिड़े इस द्वंद्व का मूल मुद्दा यही है। दोनों का ही दावा है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुपालक और रक्षक हैं। जहां तक सिद्धांतों के लिए संघर्ष और सरकार को सिद्धांत मानने के लिए बाध्य करने की बात है, इंडियन एक्सप्रेस का खाता सरकार से बेहतर है। क्योंकि सरकार के बारे में यह धारणा बन रही है कि बोफोर्स आदि आरोपों में कुछ जान होते हुए भी वह ईमानदारी से जांच करने की इच्छुक नहीं लगती। यही राजीव गांधी के लिए सबसे घातक बात है। चाहे राजस्व खुफिया निदेशालय ब्राइनर और रेणु शर्मा के कार्यों को अवैध सिद्ध कर दे और चाहे कानून यह सिद्ध न कर पाये कि राजीव गांधी ने अपने मित्रों के दुष्कर्मों को ढका है, तो भी इस झगड़े का आखिरी फैसला अदालत और नौकरशाही के बजाय जनता के हाथ में है, क्योंकि अंततः गोयनका और राजीव गांधी दोनों ही जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

छायाः गिरीश श्रीवास्तव, रंजन बसु

—रंजना कक्कड़

> सरकार के मुखिया और एक भीमकाय समाचार प्रतिष्ठान के मालिक के बीच छिड़े इस द्वंद्व का मूल मुद्दा यही है। दोनों का ही दावा है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुपालक और रक्षक हैं। जहां तक सिद्धांतों के लिए संघर्ष और सरकार को सिद्धांत मानने के लिए बाध्य करने की बात है इंडियन एक्सप्रेस का खाता सरकार से बेहतर है। क्योंकि सरकार के बारे में धारणा बन रही है कि बोफोर्स आदि आरोपों में कुछ जान होते हुए भी वह ईमानदारी से जांच कराने की इच्छुक नहीं लगती। यही राजीव गांधी के लिए सबसे घातक बात है।

camlin
Unique
PEN & BALL PEN SET
CAMLIN PVT LTD · STATIONERY DIVISION BOMBAY 400 059 (INDIA)

Camlin creates the Unique

UNIQUE from Camlin — the finest gift for all seasons. At Diwali, Christmas, Raksha Bandhan, Marriages and Anniversaries . . .

To relatives, friends, clients . . .

Whatever the occasion, give a UNIQUE gift!

Exclusive writing instruments that speak of your thoughtfulness . . . reflect your personality and good taste. Specially crafted by CAMLIN — a trusted name for over half a century.

Ask to see our full range of Pen & Ball Pen Gift Sets to suit every taste, every pocket!

camlin
Unique — in so many ways!

CAMLIN PRIVATE LIMITED, STATIONERY DIVISION, BOMBAY 400 059.

C-ENG-4

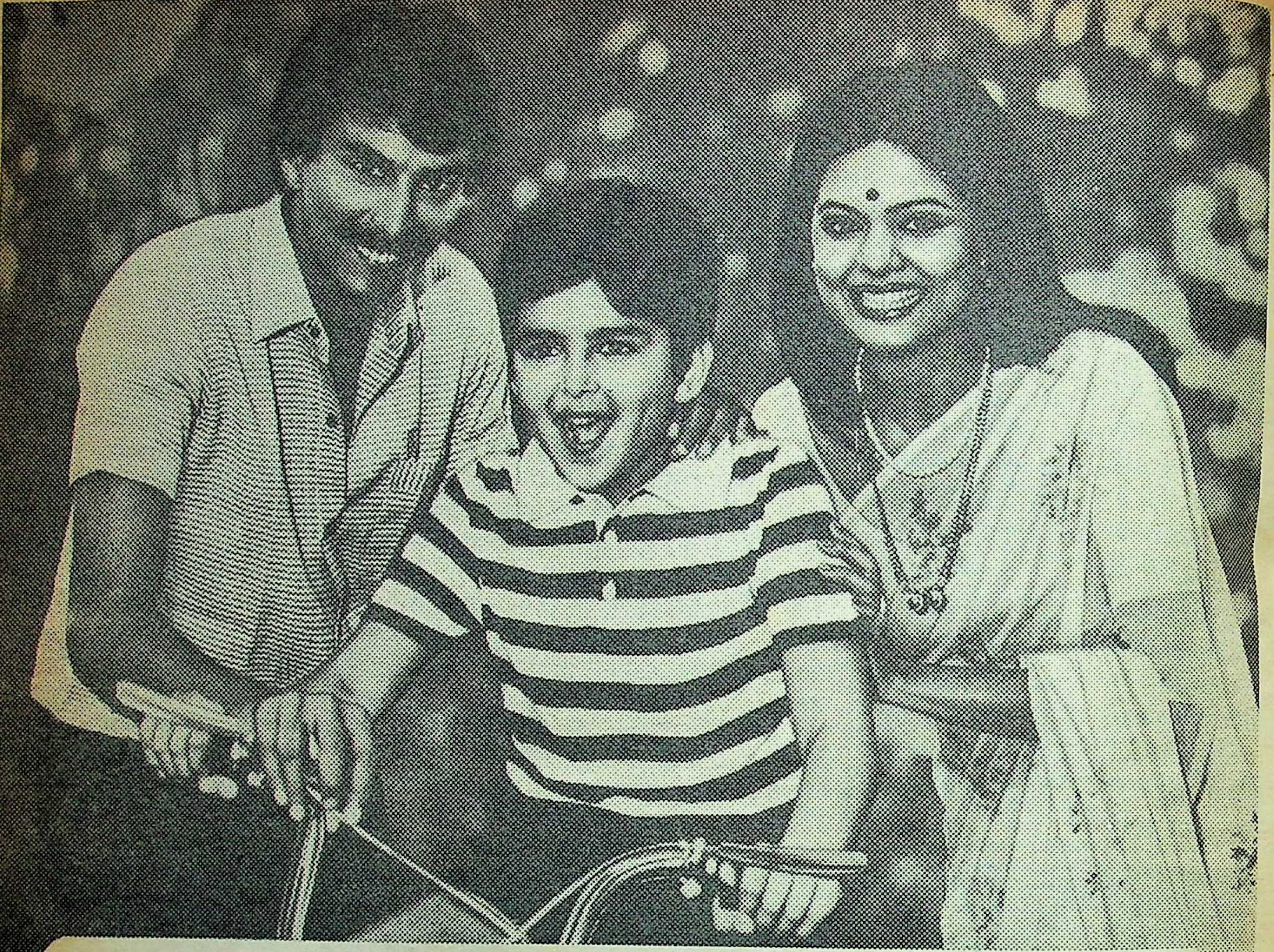

स्वास्थ्य व सुख का प्राकृतिक साधन
सेवाश्रम का स्पेशल च्यवनप्राश

सेवाश्रम का स्पेशल च्यवनप्राश, एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधी, जो आपको ताक़तवर और शक्तिशाली बनाता है। सेवाश्रम का स्पेशल च्यवनप्राश प्रकृति के उत्तम पदार्थों से तैयार किया जाता है– जैसे आँवला, अष्टवर्ग, घी, शहद, केसर, अभ्रक, भस्म, चाँदी के वर्क और अनेक जड़ी-बूटियाँ।

स्पेशल
च्यवनप्राश

bajaj group

आयुर्वेद सेवाश्रम लि., सेवाश्रम
उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद

Heros' AS-165

आबकारी विभाग

मेड़ चर रही है खेत

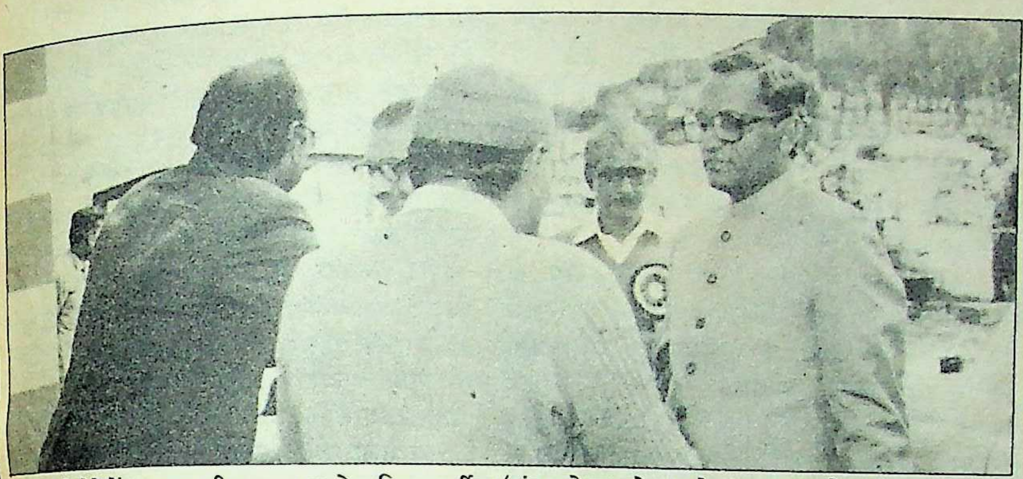

विवादों के घेरे में : आबकारी आयुक्त अशोक विजयवर्गीय (बंद गले का कोट पहने, चश्मा लगाये हुए)

मध्य प्रदेश शासन की एक चौथाई से अधिक की आय का स्रोत है, शासन का आबकारी विभाग, लेकिन चालू वर्ष में ही केवल चार जिलों में शासन को पौने दो करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। इसके लिए आबकारी आयुक्त अशोक विजयवर्गीय को ही जिम्मेदार क्यों माना जा रहा है ? :

कहावत है कि मेड़ जब खेत को चरने लगे तो खेत का भगवान ही मालिक है। मध्यप्रदेश शासन के आबकारी विभाग में इन दिनों मेड़ और खेत की कहावत चरितार्थ हो रही है। पृथक आगम के हरे-भरे खेत में मेड़ की भूमिका निभानेवाले शख्स और कोई नहीं, स्वयं आबकारी आयुक्त अशोक विजयवर्गीय हैं।

अशोक विजयवर्गीय को आबकारी आयुक्त का आला अफसरों का चहेता पद अकस्मात तब मिला था, जब कथित उत्कोच-प्रकरण के कारण दुर्गा सिह तोमर को आबकारी आयुक्त के पद से हाथ धोना पड़ा था। पूर्व लोकदल और अब इंका विधायक रमाशंकर सिह के बहनोई श्री तोमर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिह के चहेते माने जाते थे। श्री तोमर आबकारी आयुक्त के सम्मानित व शक्तिशाली पद पर बैठनेवाले पहले गैर-आई०ए०एस० अधिकारी थे। आबकारी आयुक्त पद से उनकी 'छुट्टी' से आई०ए०एस० लाबी का हर्षित होना स्वाभाविक था। जैसा कि अंदेशा था श्री तोमर के 'रुख्सत' होने के बाद यह पद फिर से आई०ए०एस० लाबी की झोली में चला गया।

हाल अहवाल : आबकारी विभाग एक ऐसा महकमा है, जहां आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी हजारों-लाखों में खेलते हैं। ऐसे में आबकारी आयुक्त का तो कहना ही क्या ? पृथक आगम विभाग से शासन को आय के लिए यह जरूरी है कि शराब की दुकानों की समय पर नीलामी हो। सरकार ने एक प्रकार से यह नीति बना ली है कि शराब की दुकानें गत वर्ष की लाइसेंस फीस की तुलना में कम से कम दस प्रतिशत अधिक में नीलाम होनी चाहिए। आबकारी विभाग के लिए यह एक प्रकार से मार्गदर्शक सिद्धांत है और इसका पालन करना एक प्रकार से परंपरा बन गया है। मगर, आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर दुकानें कभी नीलाम नहीं हुईं और नीलामी की स्थिति में दुकानें पूर्व की अपेक्षा कम दरों पर नीलाम की गयीं।

इस लिहाज से देखें तो श्री विजयवर्गीय के आयुक्त-काल में वह हुआ है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती और जो आबकारी विभाग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। श्री विजयवर्गीय लीक से हटकर चलते और विभाग की आय, क्षमता और गौरव-गरिमा में अभिवृद्धि करते तो उनकी सराहना की जाती, लेकिन उन्होंने और उनके मुख्य सलाहकार व सहयोगी आबकारी उपायुक्त ए०के० जैन ने एक-के-बाद एक ऐसे कारनामे किये कि मध्यप्रदेश शासन को करोड़ों का चूना लग गया।

ठेंकों की नीलामी : साधारण व्यक्तित्व के स्वामी श्री विजयवर्गीय के बारे में कहा जाता है कि उन्हें आबकारी आयुक्त का पद बिल्ली के भाग से छींका टूटने जैसी स्थिति में मिला। पद भार ग्रहण करने के बाद ज्यों-ज्यों उन्हें इस पद की महिमा का ज्ञान होता गया, वह विभागीय हितों से दूर होते गये। जानकार सूत्रों का कहना है कि श्री विजयवर्गीय शराब विक्रेताओं और ठेकेदारों के एक 'काकस' से घिरे हुए हैं और यह काकस येन-केन प्रकारेण आयुक्त को खुश कर अपना मतलब साध लेता है। वर्ष ८७-८८ की अवधि में अधिकांश बड़े और छोटे जिलों में शराब की दुकानों का समय पर नीलाम न हो पाना आबकारी आयुक्त की अयोग्यता व कमजोरी माना जा रहा है। कहा जाता है कि वह अपने दफ्तर का काम प्रायः उपायुक्त श्री जैन के सहारे चला रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्णय उन्हीं की सलाह से लेते हैं। उनके प्रिय पात्रों में ग्वालियर में पदस्थ आबकारी निरीक्षक जयसिह यादव का नाम लिया जाता है, जो पिछले दस सालों से ग्वालियर में जमे हैं।

श्री विजयवर्गीय पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने शराब की करोड़ों रुपए की दुकानें मार्गदर्शक सिद्धांत की सरासर अवहेलना करते हुए बीस से तीस प्रतिशत कम में अपने पसंदीदा ठेकेदारों को दीं। कतिपय प्रसंग इस प्रकार हैं, जिनमें आयुक्त के फैसलों के कारण विभाग को घाटा उठाना पड़ा :

ग्वालियर टाउन में वर्ष ८६-८७ में शराब की दुकानों की नीलामी ३ करोड़, १ लाख, ७४ हजार रुपए में हुई थी। ८७-८८ में नीलामी में विलंब के कारण डेढ़ माह दुकानें विभाग ने चलायीं। डेढ़ माह बाद साढ़े दस माह के लिए जब नीलामी हुई तो २ करोड़, १० लाख रु० की बोली पर ठेका दे दिया, जबकि साढ़े दस माह की अवधि के लिए पूर्व से दस प्रतिशत अधिक के हिसाब से सरकार को बतौर लाइसेंस फीस २ करोड़, ६८ लाख रु० की रकम प्राप्त होनी चाहिए थी। बीस प्रतिशत कम पर ठेका देने के तुगलकी फैसले के कारण विभाग को सीधे-सीधे ५८ लाख रु० का घाटा उठाना पड़ा।

वर्ष ८६-८७ में जबलपुर में जबलपुर टाउन की दुकानों की नीलामी ४ करोड़, ६७ लाख रु० में हुई थी। अगले वर्ष ग्वालियर की भांति यहां भी समय पर नीलामी नहीं हुई और दो माह दुकानें विभाग ने चलायीं। दो माह बाद जब नीलामी हुई तो दस माह कीं अवधि के लिए कायदे से ३ करोड़, ८९ लाख रु० की बोली लगनी चाहिए थी, किंतु ठेके मात्र ३ करोड़, १० लाख रु० पर दे दिये गये। पूर्वापेक्षा २२ प्रतिशत कम पर ठेके देने से शासन को ७९ लाख रु० की चपत लगी। महकमे की खिल्ली उड़ी सो अलग।

ग्वालियर में कम पर ठेका देने से श्री विजयवर्गीय उपहास एवं शिकायत के पात्र बने थे। इससे सबक लेकर उन्होंने जबलपुर में कम दरों पर ठेके खुद स्वीकृत नहीं किये, वरन, उन्हें शासन के पास भेजकर स्वीकृत करा लिया था। उन्होंने तोहमत से बचने के लिए यह सावधानी तो बरती, किंतु ग्वालियर और जबलपुर का किस्सा और जगहों पर भी दोहराया। मिसाल के तौर पर भोपाल की चार दुकानों का ठेका ८७-८८ में ९ माह, २० दिन की अवधि के लिए ८५ लाख रु० में स्वीकृत किया गया। जबकि ८६-८७ में समान अवधि के लिए इन्हीं चार दुकानों के

ठेके से शासन को १ करोड़, १८ लाख रु० की आय हुई थी, इस प्रकार २८ प्रतिशत कम पर ठेका स्वीकृत करने के कारण शासन को ३३ लाख रु० की हानि हुई। इसी क्रम में, देवास जिले में सोन-कच्छ व बागड़ी की दुकानें ८७-८८ की अवधि के लिए क्रमश: २.०६ लाख और ६.८० लाख रु० घाटे पर दी गयीं। यहां ठेका पूर्वापेक्षा क्रमश: बीस व तीस प्रतिशत कम पर दिया गया।

लंबे चौड़े मध्यप्रदेश में इस प्रकार केवल चार जिलों—भोपाल, देवास, ग्वालियर और जबलपुर में श्री विजयवर्गीय के रवैये और नीतियों के कारण शासन को १ करोड़, ७८ लाख, ८६ हजार रु० की हानि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री विजयवर्गीय ने शराब की दुकानों के ठेकों के मामले में शासकीय हित के विपरीत व्यक्तिगत हित और सनक को सर्वोपरि माना। उन्होंने वही किया, जो उनका मन हुआ और जो उन्हें भाया। कहीं तो उन्होंने तीस प्रतिशत तक कम दरों पर ठेकों को मंजूरी दे दी और कहीं दस प्रतिशत कम बोली को भी नामंजूर कर दिया। होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद और इटारसी ग्रुप की दुकानें १६ जून, ८७ से ३१ मार्च, ८८ तक की अवधि के लिए गत वर्ष की तुलना में केवल ११ प्रतिशत कम पर नीलाम हुई. लेकिन ३० प्रतिशत कम पर अन्यत्र ठेका मजूर करनेवाले आबकारी आयुक्त ने अपनी व्यक्तिगत नापसंद को तरजीह देते हुए इन्हें स्वीकृत नहीं किया। १५ जुलाई, ८७ को जब पुन: नीलामी हुई तो आठ माह की अवधि के लिए बोली गयी बोली में केवल १० प्रतिशत की कमी आयी। इसके बाद भी आयुक्त महोदय ने इसे ठुकरा दिया। शराब के धंधे से संबद्ध एक व्यवसायी ने 'माया' को बताया कि श्री विजयवर्गीय की अनिच्छा और इनकार का राज यह है कि संबंधित ठेकेदार आबकारी आयुक्त महोदय को 'खुश' करने में विफल रहे। श्री विजयवर्गीय की नीतियों का ही यह नतीजा है कि दुर्ग और दल्लीराजहरा में पिछले तीन सालों से शराब की दुकानों की नीलामी नहीं हुई है और वहां देशी शराब की दुकानें आबकारी विभाग के अफसर चला रहे हैं।

कोई कार्यवाही नहीं : श्री विजयवर्गीय के आने के बाद आबकारी विभाग की गडबड़ियों का 'कच्चा चिट्ठा' तैयार कर मुख्यमंत्री और पृथक आगम मंत्री को कब का सौंपा जा चुका है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अपनी छवि के प्रति सचेत मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। निराश होकर अब इस बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को शिकायतनामा भेजा गया है। 'माया' संवाददाता को उपलब्ध इस शिकायतनामे की फोटो प्रति के अवलोकन से पता चला कि श्री विजयवर्गीय पर २ करोड़ रु० के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। शिकायतनामे में विभागीय कार्यों में श्रीमती विजयवर्गीय के दखल का भी उल्लेख है। आबकारी आयुक्त इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, इसे जानने के लिए उनसे दो-तीन बार घर और दफ्तर पर संपर्क साधा गया, मगर रूबरू चर्चा की तो बात ही दूर, आयुक्त महोदय ने फोन पर वार्तालाप करना भी उचित नहीं समझा। हो सकता है कि श्री विजयवर्गीय के पास कहने को कोई अलग कथा हो, लेकिन शराब की दुकानों के ठेकों की नीलामी के आंकड़े आबकारी आयुक्त व आबकारी विभाग की कथा मय साक्ष्य के कहते हैं। इधर यह भी हुआ है कि महकमे में दारू-सेठों का दखल व वर्चस्व बढ़ा है। यह इसी का नतीजा है कि देशी शराब की खाली बोतलों की वापसी के दामों में बढोत्तरी की गयी है। दिक्कत यह है कि पृथक आगम मंत्री राम किशोर शुक्ल को अपने पुत्र-मोह और व्याधियो से ही फुर्सत नहीं है, अन्यथा बीते कल के समाजवादी श्री शुक्ल आबकारी महकमे की इस दुर्दशा की ओर अवश्य ध्यान देते। शराब की दुकानों की नीलामी का मामला सीधे शासन के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह श्री शुक्ल और मुख्यमंत्री श्री वोरा का दायित्व हो जाता है कि इस ओर ध्यान दें और कारगर कदम उठायें, अन्यथा आयुक्त-उपायुक्त की जोड़ी विभाग के हितों से खिलवाड़ का खेल यथावत खेलती रहेगी।

—सुधीर सक्सेना

रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
राजवैद्य
शीतल प्रसाद एण्ड संस
23, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक
रसायनवटी

बढ़ती हुई आयु, रोज़मर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर पूरे शरीर का पोषण कर पूर्ण सशक्त बनाती है। **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ, विश्वसनीय, असरदार एवं बेजोड़ आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके है। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो आयु के हर आयाम पर सतत निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

200 गोली पैकिंग रु. 70/-, 60 गोली पैकिंग रु. 27/50 स्थानीय कर अलग। स्थानीय विक्रेता से लें या वी.पी. द्वारा मंगवायें। वी.पी. खर्च रु. 10/- अलग।

निर्माता :
राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23 दरियागंज, नई दिल्ली–110002
शाखाएं : दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

SAMPAN 342

दिल्ली दरबार जब अमेठी पहुंचा !

१०, ११ और १२ अगस्त को राजीव गांधी के सुलतानपुर और रायबरेली जिलों का दौरा यों तो सूखे को समर्पित था, लेकिन इसका असली मकसद रायबरेली के सांसद अरुण नेहरू और अमेठी के विधायक संजय सिंह के विद्रोह का जवाब तलाशना था और बदली हुई परिस्थितियों में अपने जनाधार की थाह लेना था। लगभग पौने तीन साल के अंतराल के बाद राजीव गांधी अमेठी पहुंचे,तो वहां क्या हुआ ?

दरअसल, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी पैदा हो गयी थीं, जिनकी वजह से राजीव गांधी को पौने तीन साल के लंबे अंतराल के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में तीन दिन तक रुककर मतदाताओं का दुखदर्द जानने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिसंबर, १९८४ में भारी बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद राजीव गांधी अमेठी के मतदाताओं को उतना अधिक समय नहीं दे पा रहे थे, जितना वह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व देते थे। लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी कि अमेठीवासियों को उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अपने किसी-न-किसी 'दूत' को उन्होंने अमेठी की 'सेवा' में लगाये रखा था।

लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अप्रैल, १९८६ में सोनिया-राजीव की जोड़ी कोई सवा दो दिन के लिए अमेठी गयी थी। लेकिन उस समय राजीव ने कहा था, "यह मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, सरकारी नहीं।" उस समय ३ से ५ अप्रैल तक यह जोड़ी अमेठी में रही थी। कई गांवों में जाकर 'जनता-जनार्दन' का हालचाल पूछा था। चूंकि वह निजी यात्रा थी, इसलिए उस समय प्रधानमंत्री की हैसियत से न तो राजीव गांधी ने कोई घोषणा की थी और न ही कोई महत्वपूर्ण आदेश दिया था। शायद यही वजह थी कि कई स्थानों पर विकास कार्यों में लंबे घोटालों की शंका के बावजूद प्रधानमंत्री ने न तो किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई की थी और

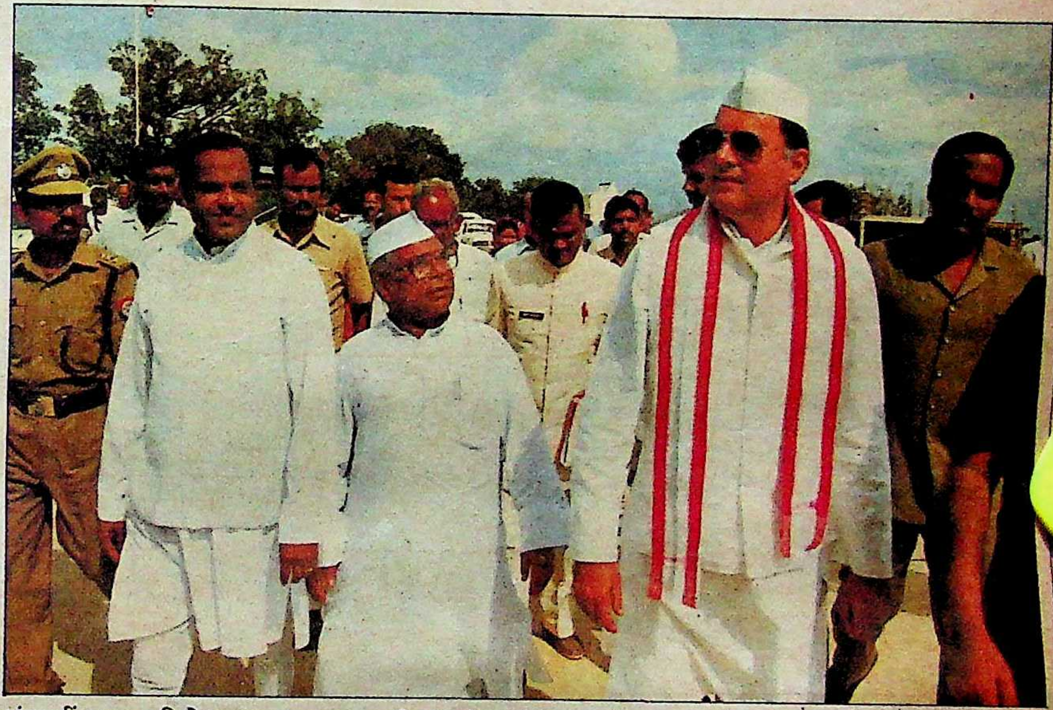

संजय सिंह द्वारा किये नुकसान का जायजा ? : राजीव गांधी, महावीर प्रसाद और वीर बहादुर सिंह

पूजा पाठ : राजीव गांधी और सोनिया गांधी

न ही वीर बहादुर सिंह से जवाब तलब किया था।

उस यात्रा के ठीक एक साल बाद ११ अप्रैल, १९८७ को यह 'जोड़ी' सरकारी यात्रा पर सुलतानपुर तो आयी थी, किन्तु व्यस्तता के कारण शहर से २५ किलोमीटर दूर स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं पहुंच सकी थी। उस दिन सुलतानपुर शहर में विकास गोष्ठी थी। अफसरों ने विकास के जो आंकड़े दे दिये थे, उन्हें सही मानते हुए गोष्ठी का समापन कर 'जोड़ी' दिल्ली उड़ गयी थी। उस समय तक इस 'जोड़ी' के चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही अमेठीवासियों के दुख-दर्द की कोई ज्यादा परवाह। उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि अगले चुनाव से पूर्व अमेठीवासियों का 'मूड' बिगड़ जायेगा।

महत्वपूर्ण घटना : २२ अगस्त को अमेठी वालों का 'मूड' अचानक खराब हो गया। जगह-जगह लोग कहने लगे—अब अमेठी की जनता १९७७ दोहरायेगी। दरअसल, उसी दिन अमेठी के राजकुमार डा० संजय सिंह, राजीव गांधी से नाता तोड़कर अपने श्वसुर राजा मांडा के खेमे में चले गये थे (देखिए 'माया' १५ सितंबर, १९८७)। उनकी इस बगावत से अमेठी की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया। मंत्री पद से इस्तीफा देकर अगले दिन (२३ अगस्त) जब राजकुमार अपने राज्य (अमेठी) में पहुंचे, तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। 'राजमहल' में उस दिन आयोजित सभा को राजा के साथ राजकुमार ने संबोधित करते हुए चेतावनी दी थी, "राजीव गांधी में हिम्मत हो, तो लोकसभा से इस्तीफा देकर दुबारा मैदान में आ कर देखें। अमेठी की जनता १९७७ का इतिहास दोहरा देगी।" प्रजा का प्रेम देख राजकुमार यहां तक कह गये थे, "राजा मांडा आदेश देंगे, तो मैं, राजीव के खिलाफ चुनाव मैदान में कूद पड़ूंगा।"

इसी प्रजा के बीच अमेठी विधानसभा क्षेत्र के तीन ब्लाक प्रमुख रामहर्ष सिंह, राम बहादुर सिंह और रणवीर सिंह भी उपस्थित थे। इन तीनों ने नारा लगाया, "संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।" ऐसा ही नारा अमेठी संसदीय क्षेत्र के करीब एक हजार इंका कार्यकर्ताओं ने भी उस दिन लगाया था।

दरबार में खलबली : बस इसी घटना के बाद से दिल्ली दरबार में हलचल मच गयी थी। यह अफवाह फैलने लगी कि राजीव गांधी अब अगला चुनाव अमेठी से नहीं लड़ेंगे। वह दक्षिण में कोई सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश कर रहे हैं। इस अफवाह को उस समय और भी बल मिला, जब राजा मांडा, अरुण नेहरू और मेनका गांधी ने घोषणा की, "अक्तूबर, १९८७ के पहले सप्ताह में हम लोग संयुक्त रूप से अमेठी में एक विशाल सभा करेंगे तथा राजीव गांधी पर दबाव डालेंगे कि वह अमेठी से इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़ें।" इस पूर्व घोषित 'विशाल सभा' के आयोजन की तैयारी भी शुरू हो गयी थी। इसी अफवाह से अमेठीवासी भ्रमित थे। वहां के इंकाइयों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें?

बाबा के प्रभाव का प्रसाद : प्रसाद लेते हुए राजीव गांधी

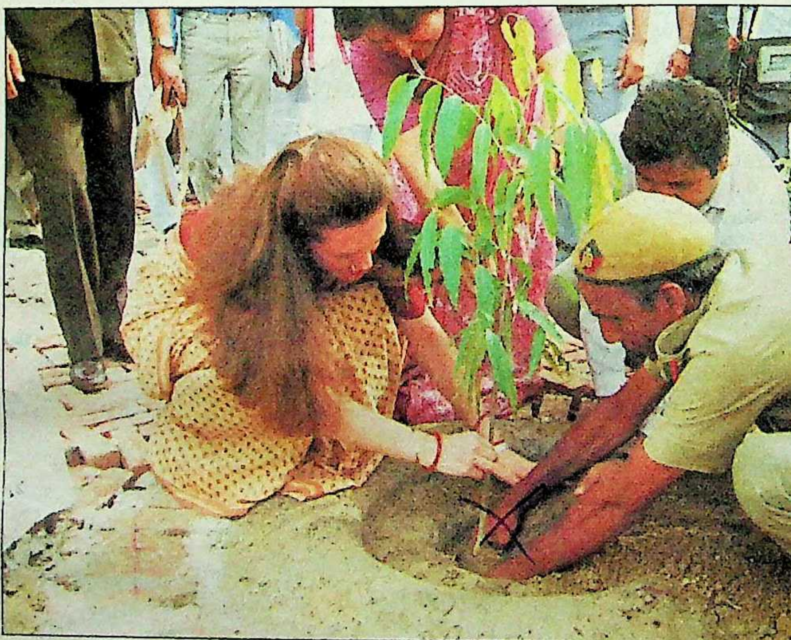

जड़ें जमाने की कोशिश : सोनिया वृक्षारोपण करते हुए

तब दिल्ली दरबार को लगा कि इस मामले में कुछ-न-कुछ जरूर करना चाहिए। यद्यपि इस बीच वीर बहादुर सिंह, अमेठी के तमाम इंकाइयों को अपने सरकारी घर में बुलाकर 'जलपान' करा चुके थे। उन्हें समझा-बुझाकर न केवल 'ठीक' कर लिया गया था, वरन उनसे उस निष्ठा प्रपत्र पर दस्तखत भी करा लिये गये थे, जिसमें लिखा था, "संजय सिंह का कहीं कोई वजूद नहीं है। हम सब निष्ठापूर्वक राजीव भैया के साथ हैं।"

इस बीच आलाकमान ने रणनीति तैयार कर ली थी। इस रणनीति के तहत उन लोगों को आगे लाया जाने लगा, जिन्हें संजय सिंह ने कान भर कर दरबार से दूर करा दिया था। इसी क्रम में सबसे पहले केदारनाथ सिंह आगे लाये गये। वर्ष १९७७ के चुनाव से पूर्व तक केदारनाथ सिंह न केवल सुलतानपुर से सांसद थे, वरन इंदिरा-सरकार में राज्यमंत्री के पद पर भी थे। उसके बाद जनता-आंधी में वह चुनाव हार गये थे। १९८० में जब पुन: चुनाव होने वाले थे, तो संजय सिंह ने संजय गांधी से कह कर केदारनाथ सिंह का टिकट कटवा दिया था। यहीं से केदारनाथ सिंह और संजय सिंह की दुश्मनी शुरू हो गयी थी। संजय सिंह जब तक 'पावर' में रहे, केदारनाथ सिंह को उन्होंने उठने नहीं दिया। १९८४ के लोकसभा चुनाव में तो संजय सिंह ने केदारनाथ सिंह को शहर-बदर ही करा दिया। उन्हें सुलतानपुर से हापुड़ (गाजियाबाद) भिजवा दिया।

नये सिपहसालार : इसी तरह अमेठी में एक राजा का प्रभाव समाप्त करने के लिए आलाकमान ने दो राजाओं (राजा दिनेश सिंह और राजा मोहन

सफर की तैयारी

सिह) को बढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों पर जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वे अमेठी संसदीय क्षेत्र में ठाकुरों के बिगड़े 'मूड' को ठीक करें। ब्राह्मणों का सम्मान बनाये रखने के उद्देश्य से श्रीपति मिश्र (भूतपूर्व मुख्यमंत्री) और शिवप्रसाद मिश्र उर्फ बाबा मिश्रा को पुनः सक्रिय कर दिया गया। यह भी एक विडम्बना ही है कि सुलतानपुर की राजनीति में केदारनाथ सिह और श्रीपति मिश्र के बीच हमेशा से छत्तीस का रिश्ता रहा है, लेकिन अब मुसीबत के समय दिल्ली दरबार ने दोनों को ही 'काम पर' लगा दिया है।

प्रतापगढ़वासी बाबा मिश्रा एक समय में संजय गांधी के काफी करीब थे। १९७७ का चुनाव लड़ने से पूर्व संजय गांधी ने अमेठी क्षेत्र में जो सबसे पहला श्रमदान शिविर आयोजित किया था, उसके इन्चार्ज बाबा मिश्रा ही थे, लेकिन जब संजय गांधी के दरबार में संजय सिह की पूछ बढ़ गयी, तो बाबा मिश्रा, नजरअंदाज कर दिये गये। अब उन्हें फिर से अमेठी में 'फिट' किया गया है। संजय सिह द्वारा एक समय में उपेक्षित किये गये पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता तथा सेवादल के प्रादेशिक अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और अमेठी कैम्प के कमांडर प्रवीर बागची का भी पूरी तरह से अमेठी क्षेत्र में लगा दिया गया।

ये सारी गोटें बिठाने के बाद दिल्ली दरबार ने तय किया कि अब 'जोड़ी' को 'अपनों के बीच' जाना चाहिए। तारीख तय हुई १० से १२ सितम्बर तक। इस बीच यह भी तय किया गया कि अमेठी कस्बे में ही एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जाये, जिसमें राजीव भैया, अपने खिलाफ फैली अफवाहों का निराकरण करें। 'जोड़ी' का दौरा-कार्यक्रम पूरी तरह तय हो गया। यह सब इतनी जल्दी में तय हुआ कि अफसरों की दुर्व्यवस्था पर कलई करने का मौका ही नहीं मिल पाया।

राजीव गांधी को पहली बार यह महसूस हुआ कि अपनी इस यात्रा को जोरशोर से प्रचारित कराया जाये। शायद इसलिए जब वह अपनी अर्धांगिनी के साथ दिल्ली से रवाना हुए, तो कुछ गिने-चुने पत्रकारों और दूरदर्शन की टीम को साथ लेना नहीं भूले। १० सितम्बर को अपराह्न फुरसतगंज (रायबरेली) हवाई अड्डे पर वायुसेना के विमान से 'जोड़ी उतरी', तो पीछे-पीछे राजा दिनेश सिह भी पत्रकारों की टीम के साथ उतरे। स्वागतकर्ताओं को एक चीज का अभाव जरूर अखरा, वह था कैप्टन सतीश शर्मा की अनुपस्थिति।

हवाई अड्डे पर सुरक्षा-व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि वीर बहादुर सिह की सरकारी गाड़ी को 'बिना पास' बताकर गेट पर ही सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। कार का शीशा उतार कर जब वीर बहादुर ने बाहर झांक कर कहा, "मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे तो जाने दो"—तब कहीं उन्हें जोड़ी के स्वागत हेतु प्रवेश मिला। आबकारी राज्यमंत्री रामनाथ मुंशी, इंका के प्रादेशिक महामंत्री गुलाब सेहरा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र को काफी हीला-हवाली के बाद स्वागत के लिए जाने दिया गया।

'रनवे' पर 'जोड़ी' का स्वागत करने के लिए चूंकि वीर बहादुर और प्रदेश इंका अध्यक्ष महावीर प्रसाद के अलावा किसी अन्य नेता और मंत्री को जाने नहीं दिया गया था, इसलिए सब ऐंकर (हवाई जहाज के लंगर डालने के लिए बना टिन शेड) में कतार बांधकर खड़े हो गये थे। इसी बीच मुख्यमंत्री की कुरसी पर नजर गड़ाये बैठे स्वास्थ्य-मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने खासा ड्रामा किया। कतार में खड़े लोगों से मिलते हुए राजीव और सोनिया जैसे ही लोकपति के पास पहुंचे, तो ठीक काशी के पंडे की तरह लोकपति ने सदरी की जेब से एक डिब्बिया निकाली। उसमें घिसा हुआ चंदन और सिंदूर था। चंदन लगाया राजीव गांधी के माथे पर और सिंदूर लगाया सोनिया गांधी के। फिर दोनों के कपड़ों पर इत्र लगाकर माला भेंट कर दी। हाल में प्रदेश इंका समिति में महासचिव के पद पर स्थापित किये गये बच्चा पाठक और गुलाब सेहरा तो साष्टांग दण्डवत करना नहीं भूले।

इसके बाद शुरू हुआ जनसंपर्क कार्य। जोंगा जीप में ड्राइवर की जगह खुद, बगल में सोनिया गांधी और पीछे सीट पर मुख्यमंत्री को बिठा कर तूफानी गति से ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर जीप चलाते हुए राजीव गांधी गांव-गांव पहुंचे और सूखे तथा अन्य समस्याओं से पीड़ित ग्रामीणों से मिले। रोखा गांव में तीन वृद्धाओं को तुरंत पेंशन दिलवाने की व्यवस्था की, तो मौजा विश्रामपुर में मित्रदीन नामक ग्रामीण के बीमार बेटे का अपने चिकित्सक से परीक्षण करवाया और दवा दिलवायी। यह स्थिति रात नौ बजे तक रही। इसके बाद पूरा काफिला तातारपुर स्थित सिंचाई विभाग के

डाक बंगले पहुंचा। वहां सुरक्षा का इतना तगड़ा इंतजाम था कि हरिजन कल्याण मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी, कृषिमंत्री नरेंद्र सिह, राज्य मंत्री शिव बालक पासी, सहकारिता मंत्री अरुण कुमार सिह 'मुन्ना' को भी तलाशी देनी पड़ी। डाक बंगले में दिल्ली दरबार ने वीर बहादुर सिह, नरेंद्र सिह और तिलोई के राजा मोहन सिह से करीब आधे घंटे एकांत में मंत्रणा की। कई लोगों को शिकायत थी कि राजा दिनेश सिंह दो दिन पहले अमेठी के राजमहल में क्यों गये थे ? जब संजय सिह ने इतनी बड़ी दगाबाजी की है, तो उनके पिता से दिनेश सिंह क्यों समझौता कर रहे हैं ? राजीव गांधी ने सफायी दी, "दिनेश सिंह के अमेठी के राजा से पुराने संबंध हैं। उन्होंने (अमेठी के राजा) दिनेश सिंह को एक चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया था कि वह बहुत बीमार हैं और उनके लड़के सजय सिंह ने गलती कर दी है, उसे माफ करा दें तथा उन्हें देखने आ जायें। इसीलिए दिनेश सिंह, अमेठी राजमहल में उन्हें देखने गये थे।"

राजीव गांधी की ओर से सतीश शर्मा अमेठी की देखभाल करते हैं, लेकिन १० सितंबर को उनकी अनुपस्थिति आश्चर्यजनक थी। वह ११ सितंबर को तातारपुर पहुंचे। लेकिन जब दिल्ली दरबार टीकर माफी आश्रम पहुंचा, तो वहां के स्वामी चैतन्य ब्रह्मचारी ने उनकी शिकायत कर दी, "सतीश शर्मा इस आश्रम को कोई महत्व नहीं देता है। उसका काम भी ठीक नहीं है।" बताया जाता है कि टीकर माफी आश्रम के एकांत कमरे में एक अनुष्ठान के समापन में भी राजीव और सोनिया ने भाग लिया। यह अनुष्ठान राजीव को सत्ता में बनाये रखने के उद्देश्य से स्वामी चैतन्य ब्रह्मचारी पिछले एक महीने से कर रहे थे। अनुष्ठान के समापन के बाद स्वामीजी ने मिठाई के दो पैकेट, फल और दो फूलों के साथ आशीर्वाद दिया, "आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आपकी यह जोड़ी पूरे विश्व में नाम कमायेगी।" टीकर माफी आश्रम के बाद जब राजीव का काफिला संग्रामपुर पहुंचा, तो वहां के ब्लाक प्रमुख रणधीर सिंह ने दिल्ली दरबार के सामने घोषणा की, "मैंने संजय सिह का साथ छोड़ दिया है। अब आपकी शरण में आ गया हूं।" इसी तरह भेटुवा ब्लाक के प्रमुख राम हर्ष ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों ब्लाक प्रमुखों ने २३ अगस्त को संजय सिंह का साथ देने की घोषणा की थी। जहां तक ग्रामीणों की शिकायतों का सवाल है, वे केवल सूखे तक ही सीमित नहीं थीं। भ्रष्टाचार से पीड़ित होने की शिकायतें भी राजीव से की गयीं। कसौली का पुरवा गांव में एक ग्रामीण ने शिकायत की, "मुझे जमीन का जो सरकारी मुआवजा मिला था, उसमें से दो हजार रुपए एक अफसर ने गैस चूल्हा खरीदने के नाम पर कमीशन ले लिया है।" जामों ब्लाक के इंका अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने शिकायत की, "अमेठी भ्रष्ट अफसरों का चारागाह बन गया है। विकास के लिए यहां काफी पैसा आ रहा है, इसलिए हर भ्रष्ट अफसर अपनी पोस्टिंग यहीं चाहता है। खुद इंका के लोग विकास का धन और पार्टी-प्रचार का पैसा खा रहे हैं।"

दिल्ली दरबार
की इस यात्रा से अमेठी
और रायबरेली के इंका कार्यकर्ताओं में
नयी जान आयी है, लेकिन यह चेतना
अधिक समय तक बनी रहेगी, इसमें
संदेह है। खुद इंकाइयों को इस बात का
भय है कि कहीं राजा मांडा के दौरे
के बाद हालात फिर न
बदल जायें।

आश्रमों की राजनीति

भेटुआ से जब राजीव का काफिला अमेठी की ओर बढ़ा, तो रास्ते में अमेठी का राजमहल भी पड़ा, लेकिन एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ। हां, अमेठी कस्बे में पहुंचते ही स्वागत में इतनी भीड़ उमड़ी कि राजीव गांधी दंग रह गये। पूरा इलाका स्वागत द्वार और झंडे बैनरों से पटा हुआ था। यह देख राजीव गांधी ने वीर बहादुर की ओर मुखातिब होकर कहा, "अगर ऐसा पता होता, तो यहां की पब्लिक मीटिंग कैंसिल न करता।" यहीं दरबार को एक नया नारा सुनायी पड़ा, "राजीव गांधी तुम देश को देखो, हम संजय सिह को देखेंगे।"

शाम को गौरीगंज में इंका कार्यकर्ताओं की सभा थी। दिल्ली दरबार के वहां पहुंचने के पूर्व ही कार्यकर्ताओं के दो गुटों में जमकर मारपीट हो चुकी थी। हुआ यह कि सभा का संचालन कर रहे विधान परिषद सदस्य रामदुलारे यादव ने भाषण के लिए मंच पर सुलतानपुर जिला इंका अध्यक्ष उदय प्रताप सिह को आमंत्रित कर दिया। उदय प्रताप सांसद श्रीपति मिश्र के गुट के थे। उन्होंने मंच से जब सांसद केदारनाथ सिह को गद्दार कहा, तो केदारनाथ सिह समर्थक कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरन मंच से खींच कर उनकी पिटायी करनी चाही। तब तक श्रीपति मिश्र-समर्थक कार्यकर्ता आगे आ गये। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। कइयों के कपड़े फट गये। तब राम दुलारे यादव को मंच के संचालन कार्य से हटाकर उन्हें सभा स्थल से बाहर कर दिया गया। इसी सभा में राजीव गांधी ने इस बात का खंडन किया कि वह अमेठी से चुनाव न लड़ने की बात सोच रहे हैं। तीसरे दिन का दौरा रायबरेली क्षेत्र का था। वहां अरुण नेहरू का कोई प्रभाव दिखायी नहीं पड़ा। हां, संजय मंच के गढ़ इन्होंना में कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाने का असफल प्रयास जरूर किया।

रायबरेली में दिल्ली दरबार ने एक इशारा जरूर किया। वहां एक सार्वजनिक सभा में कहा, "रायबरेली से हमारा पैतृक संबंध है। इस रिश्ते को हम टूटने नहीं देंगे। अब अमेठी और रायबरेली के बीच विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं होगा। अमेठी और रायबरेली एक सिक्के के दो पहलू होंगे। दिल्ली दरबार का इतना कहना था कि भीड़ से एक साथ कई लोगों ने मांग की, "यहां से सोनियाजी को लड़ाइए।" दिल्ली दरबार ने कनखियों से सोनिया की ओर देखा। सोनिया जमीन की ओर देख रही थीं। राजीव मुस्करा कर रह गये।

दिल्ली दरबार की इस यात्रा से अमेठी और रायबरेली के इंका कार्यकर्ताओं में नयी जान आयी है, लेकिन यह चेतना अधिक समय तक बनी रहेगी इसमें संदेह है। खुद इंकाइयों को इस बात का भय है कि कहीं राजा मांडा के दौरे के बाद हालात फिर न बदल जायें।

—अमेठी से, अजय कुमार और निशीथ जोशी

छाया : मन मोहन शर्मा

आदिवासी अंचल में यौन शोषण

मजदूरी में मिला नाजायज बेटा: समाज-बहिष्कृत सोम्बारी अपने नाजायज बच्चे के साथ

सिहभूम, छोटा नागपुर और संथाल परगना के अंचलों में प्रायः हर आदिवासी गांव में पांच-सात ऐसी आदिवासी लड़कियां जरूर मिल जायेंगी जो नाजायज बच्चा पैदा करने के अपराध में आदिवासी समाज से बहिष्कृत करके नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दी गयी हैं। ये नाजायज बच्चे किसी प्रेम-प्रसंग का परिणाम नहीं होते, बल्कि गरीबी की मार से बेबस हुई लड़कियों को ईंट-भट्ठों के ठेकेदार बहलाफुसला कर ले जाते हैं, मामूली सी मजदूरी में हाड़तोड़ मेहनत करवाते हैं और अपनी और अपने कारिंदों की हवस का शिकार भी बनाते हैं। बहुत सी आदिवासी मजदूरिनों को देह-व्यापार के लिए ये ठेकेदार बेच भी देते हैं। ऐसी १५ हजार लड़कियां लापता हैं, लेकिन जो घर लौटती हैं, उनके गर्भ में होता है उन ठेकेदारों का नाजायज बच्चा, जिन्हें ये आदिवासी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अपनी कन्याओं के गर्भ में इन दुश्मनों की नाजायज संतान को पलते देखकर वे इन्हें बड़ी आत्मपीड़ा से समाज बहिष्कृत कर देते हैं, लेकिन छटपटाकर रह जाते हैं, इन ठेकेदारों के खिलाफ कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जंगल में अब असंतोष की आग धीरे-धीरे जोर पकड़ती जा रही है। खुद आदिवासी महिलाएं इस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संगठित हो रही हैं। यदि शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो किसी भी क्षण इन आदिवासी अंचलों से उठी आग दीघा से मोकामा तक के सभी सात सौ से अधिक ईंट-भट्ठों को जलाकर राख कर देगी? आदिवासी लड़कियों के उत्पीड़न और जंगलों में शोला बन रहे असंतोष का विकास कुमार झा द्वारा आकलन:

महज ढाई साल का सोमा अनजान है, दुनिया के तमाम दुखों से। उसे भला क्या पता कि खुद वही अपने आप में एक जीता-जागता दुख है, अपनी मां सोम्बारी जामदा के लिए। सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल के तहत एक छोटा सा गांव है, बायंका। पहाड़ की तलहटी में बसे इसी गांव में सोम्बारी जामदा असहनीय दंड भोग रही है। पर कसूर सोम्बारी का तो कुछ भी नहीं। सोम्बारी का बाप दापु जामदा, उसकी मां और परिवार के सभी लोग बस तड़प कर रह जाते हैं, सोम्बारी की यह दशा देखकर। पर वे कुछ भी नहीं कर सकते। गांव की पंचायत ने उसे दंड दे रखा है कि अपने मां-बाप के संग वह नहीं रह सकती, क्योंकि सोम्बारी एक कुंवारी मां है। यानी सोमा उसका नाजायज बेटा! लिहाजा, बायंका गांव से दूर कुछ हटकर निर्जन में अकेले सोम्बारी अपने छोटे से बच्चे को लेकर पिछले तीन सालों से समाज-बहिष्कार की सजा भोग रही

बेबस पिता: सोम्बारी की मौत की कामना करता हुआ पिता दामु जामदा

दुश्मन के बच्चों का गला घोंटना होगा: मांदुई होनाहागा

प्रतिशोध की शुरुआत: आदिवासी महिलाओं के संगठन का जंगल स्थित कार्यालय

है। उसका बाप दामु जामदा उसी दुख में जो बीमार पड़ा सो आजतक उसकी हालत नहीं सुधरी है। दामु कहता है, "सोम्बारी अगर मर गयी होती न, तो इतना दुख नहीं होता मुझे। पर रोज उसे इस बदहाली में देखकर छटपटाता रहता हूं। अब उसकी शादी भी तो कभी नहीं होगी। जीवन भर उसे ऐसे ही समय गुजारना होगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं। समाज का यही फैसला है।"

शोषण का तरीका: यह व्यथा अकेले सोम्बारी की ही नहीं। सिर्फ एक बायंका गांव में ही इस तरह का संकट झेल रही चार-पांच लड़कियां हैं जो अपनी जारज संतानों के कारण समाज-बहिष्कृत हैं। इन्ही में से एक जांबी नाम की लड़की भी है, जिसने कुछ समय पूर्व ही एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है। पूरे सिंहभूम के अंचल में औसतन प्रति गांव में चार-पांच की संख्या में ऐसी हजारों कुंवारी मां हैं। सवाल यह है कि इन आदिवासी लड़कियों के गर्भ में इन नाजायज बच्चों को कौन डालता है? दरअसल इसके पीछे यहां की भीषण भुखमरी है। प्रतिवर्ष ईंट-भट्ठों में काम करने के लिए भट्ठे के ठेकेदार इन सुदूर आदिवासी अंचलों से हजारों-हजार आदिवासी लड़कियों को पैसे का लालच देकर उनके मां-बाप की अनुमति से ले जाते हैं। बरसात के समय जब ये लड़कियां धान की रोपनी के लिए वापस अपने-अपने गांव लौटती हैं तो पारिश्रमिक के तौर पर उनके गर्भ में होता है ईंट-भट्ठों के ठेकेदारों का नाजायज बच्चा। फिर तो पूरा परिवार ही अभिशप्त हो जाता है। दिक्कू (गैर आदिवासी) जिनसे वे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उनका बच्चा एक आदिवासी लड़की की कोख में। पूरे आदिवासी गांव में बेचैनी फैल जाती है। सोम्बारी जामदा भी आज से तीन साल पूर्व खड़गपुर के ईंट-भट्ठे पर काम करने ले जायी गयी थी। एक रात भट्ठे के ठेकेदार ने सोम्बारी के साथ जबर्दस्ती की। सोमा का गर्भ उसी बदनसीब रात को उसकी कोख में ठहर गया।

सोम्बारी पूछती है कि उसकी जिंदगी तो जैसे-तैसे कट जायेगी, पर क्या उसका आदिवासी समाज सोमा को स्वीकार करेगा? क्या होगा आदिवासी अंचल में पल रहे हजारों सोमा जैसे बच्चों का। सोम्बारी कहती है, "इससे तो भाग्यशाली वही लड़कियां निकलीं, जिन्हें भट्ठे के ठेकेदार ने उनके गांव वापस न भेजकर देह व्यापार के अड्डे पर भेज दिया।" भट्ठे में काम करने गयी लड़कियों में से दर्जनों को कलकत्ता और बिहार में देह-व्यापार के अड्डों पर बेच दिया जाता है।

लापता आदिवासी कन्याएं: चक्रधरपुर के भाजपा विधायक जगन्नाथ बांकिरा के घर में भी एक ऐसा ही हादसा हो चुका है। चक्रधरपुर से सिर्फ चार किलोमीटर दूर इंडीकाटा गांव की जेमा कुई जगन्नाथ बांकिरा के पिता की अपनी चचेरी बहन थी। महज पन्द्रह साल उम्र थी उसकी जब सौ रुपये एडवांस देकर भट्ठे का ठेकेदार जेमाकुई को १९७७ में बैरकपुर के ईंट-भट्ठे पर ले गया था। जगन्नाथ बांकिरा कहते हैं, "आज दस साल बीत गये पर जेमा का कोई पता नहीं चला। भट्ठे के ठेकेदार ने शायद उसे देहव्यापार के किसी दलाल के हाथों बेच दिया। कहां नहीं तलाशा हमने उसे, पर न वह ठेकेदार मिला न ही जेमाकुई मिली। ईंट-भट्ठों में आदिवासी लड़कियों के शोषण के सवाल पर मैंने विधान सभा में भी कई बार हंगामा किया, पर सरकार की तरफ से कोरे आश्वासनों के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला।"

बिहार में दीघा से लेकर मोकामा तक गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में सात सौ के आसपास ईंट-भट्ठे हैं। भट्ठे का ठेकेदार सिंहभूम, छोटानागपुर और संथालपरगना से उरांव, मुंडा एवं हो जाति की आदिवासी लड़कियों को थोक के भाव ले आते हैं। आदिवासी लडकियां इन ठेकेदारों के लिए हर दृष्टिकोण से फायदेमंद हैं। एक तो जीतोड़ मेहनत कर वे भट्ठे में काम करती हैं, दूसरे ठेकेदार व उसके कारिंदों को देह का सुख भी देती हैं और तीसरे उन्हें बेचकर काफी पैसे भी मिल जाते हैं।

औरत सरदारिन की भूमिका: ईंट-भट्ठों में इन आदिवासी लड़कियों को लाने में एजेंट के तौर पर कोई आदिवासी मर्द या औरत ही होते हैं। ये सरदार-सरदारिन कहलाते हैं। औरत सरदारिन की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर उस पर किसी को संदेह भी नहीं होता है। भट्ठे का मुंशी जो गैरआदिवासी होता है, अगस्त से सितंबर के बीच हर साल औरत सरदारिनों के संग आदिवासी मजदूरिनों को फंसाने के लिए सिंहभूम व छोटानागपुर के अंचल में आता है। औरत सरदारिनें मुंशी को किसी से मिलने नहीं देतीं। वे मुंशी से एडवांस के पैसे लेकर गांव-गांव में निकल पड़ती हैं। अगस्त से सितंबर का महीना आदिवासियों के लिए काफी कष्टप्रद रहता है। अनाज की कमी रहती है। लिहाजा, औरत सरदारिनों की रुपए से भरी मुट्ठी के आगे विवश होकर ये अपनी बेटियों को उनके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। भट्ठे पर जाने के पूर्व लड़कियों के मां-बाप को अग्रिम कुछ पैसे दिये जाते हैं, जिसे 'दादान' कहा जाता है। ये आदिवासी लड़कियां आमतौर पर १०० रुपए से १५० तक के 'दादान' पर बुक कर दी जाती हैं। बहरहाल, सौ-डेढ़

सौ रुपये का 'दादान' निरीह आदिवासी लड़कियों के लिए दुर्भाग्य के दौर की शुरुआत लेकर आता है। ईंट-भट्ठों में ईंट ढोने, चढ़ाने और भट्ठी सुलगाने का काम करना पड़ता है। ४०० गज से ५०० गज तक सिर पर कच्चा ईंट ढोने के लिए इन्हें एक टोकन मिलता है। एक सौ टोकन यानी एक हजार ईंट दिनभर ढोने पर मात्र छह रुपए मजदूरी मिलती है। इसी तरह एक हजार ईंट सिर पर ढोने के लिए महज पांच रुपए मिलता है। एक हजार ईंट बनाने की मजदूरी सिर्फ चौदह रुपए मिलती है। सप्ताह में विश्राम के दिन का कोई भुगतान नहीं होता तिस पर पारिश्रमिक का आंशिक भुगतान ही किया जाता है, इस तर्क के साथ कि जब वे अपने गांव जानें लगेंगी, तो बाक़ी पैसे दे दिये जायेंगे। पर वापसी के वक्त एक पैसा नहीं दिया जाता, यह कर कर कि 'दादान' के एवज में पैसे काट लिये गये हैं। हां, एक मामूली साड़ी जरूर दी जातीं है, ताकि गांव में सबको लगे कि इसे वहां पहनने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी।

अब मुकाबला होगा : पूर्णेदुं मजूमदार

अदालत में पहुंचे मामलेः भट्ठों में कार्यरत इन मजदूरिनों पर जुल्म के इक्के-दुक्के मामले ही अदालत तक पहुंच पाते हैं। कानून की न तो इन निरीह लोगों को जानकारी ही है और न ठेकेदारों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का साहस ही। फिर भी पिछले दिनों में एकाध केस अदालत में गये, पर हुआ कुछ भी नहीं। मुजफ्फरपुर न्यायालय में मैसर्स ओटनमल सिंधी का १९७९ में एक आदिवासी मजदूरिन के साथ हुआ बलात्कार का मामला अभी तक विचाराधीन ही है। १९८१ में भोजपुर के डुमरांव में इसी तरह आदिवासी मजदूरिनों के बलात्कार का मामला अदालत तक गया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के छोटानागपुर और सिंहभूम अंचल से तकरीबन पन्द्रह हजार लड़कियां लापता हैं। उनके मां-बाप रो-पीटकर रह गये, पर उनकी बेटियां नहीं मिल सकीं। ठेकेदारों और गिरोहों द्वारा बहलाफुसलाकर ये लड़कियां ले जायी गयीं, तो फिर कभी नहीं लौट सकीं। देहव्यापार के अड्डों पर बेचे जाने के अलावा इन लड़कियों को सऊदी अरब व कुछ अन्य देशों में भी समुद्री मार्गों से या अन्य तरकीबों से भेजकर बेचे जाने की खबर निराधार नहीं। पर कौन जहमत उठायेगा जंगल की इन बेटियों पर गुजरती नबाही को टालने की।

हम संघर्ष करते रहेंगे : लारो जोंको

संघर्ष की आगः सिंहभूम में आदिवासियों के इस तरह के शोषण के खिलाफ गांव-गांव में घूमकर दो लोग सर्मपित संघर्ष कर रहे हैं। ये हैं, ५६ वर्षीय पुर्णेन्दु मजूमदार और ३५ वर्षीया आदिवासी युवती लारो जोंको। पुर्णेन्दु कहां के हैं, ये वह खुद भी नहीं बताना चाहते। पर कुछ लोग कहते हैं कि वे बंगलादेश के मूल निवासी हैं, तो कुछ का कहना है कि वह पश्चिम बंगाल के हैं। बहरहाल, १९५४ में पुर्णेन्दु आदिवासियों के बीच काम करने आये, तो बस यहीं के होकर रह गये। इस इलाके में पहले-पहल उन्होंने गुआ और बड़ा जामदा के लौह खदानों में कार्यरत आदिवासी लोडिंग मजदूरों के शोषण के खिलाफ झंडा लहराया। फिर तो सिंहभूम के हर खदान में संघर्ष का यह सिलसिला बढ़ता ही गया। पुर्णेन्दु ने एटक से सम्बद्ध 'यूनाइटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन' का गठन किया, जिसका मुख्यालय उन्होंने बायंका में ही बना रखा है। क़ई वर्षों तक़ मेनस्ट्रीम के संपादक निखिल चक्रवर्ती की सांसद पत्नी रेणु चक्रवर्ती इस संगठन की अध्यक्ष थीं और पुर्णेन्दु इसके सचिव पर अभी इसके अध्यक्ष कम्युनिस्ट सांसद इन्द्रजीत गुप्त हैं। पुर्णेन्दु पहले चाईबासा और गुआ के क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय थे। पर ८ मार्च, १९७९ को जब चक्रधरपुर से कुछ दूर लोटापहाड़ में स्थित 'चिरीबुरु क्वार्ट जाइट मिनरल माइंस' में तालाबंदी हुई, तो वहां के आदिवासी मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने पुर्णेन्दु यहां आ गये। पुर्णेन्दु कहते हैं कि माइंस आज तक बंद पड़ी है और सरकार को निरीह आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं। चिरीबुरु की तालाबंदी का कारण यह है कि बिहार सरकार ने 'मैसर्स उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड' के पुनर्नवीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया। डालमिया अधिकृत भारत सिमेंट ने १९५६ में खान को बंधक पर २० वर्षों के लिए लिया था, पर इसके पश्चात इसके सहयोगी संगठन 'मेसर्स उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड' को १९६३ से हस्तांतरित कर दिया गया। लीज की मियाद खतम होने पर बिहार सरकार ने लीज का पुनर्नवीकरण करना अस्वीकार कर दिया। नतीजतन, लगभग दो हजार से भी अधिक आदिवासी खान मजदूर बेरोजगार हो गये। इन दो हजार मजदूरों में पन्द्रह सौ से ऊपर तो आदिवासी लड़कियां थीं। पुर्णेन्दु कहतें है कि बेरोजगारी और गरीबी में ये मजदूरिनें ईंट-भट्ठों के ठेकेदारों के हाथ फंसने लगीं। फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, कलकत्ता, बेलगछिया तथा अन्य कई जगहों पर गयी लड़कियों में से तो बहुत लौटी ही नहीं और जो लौटीं भी तो पेट में अवैध शिशु लेकर।

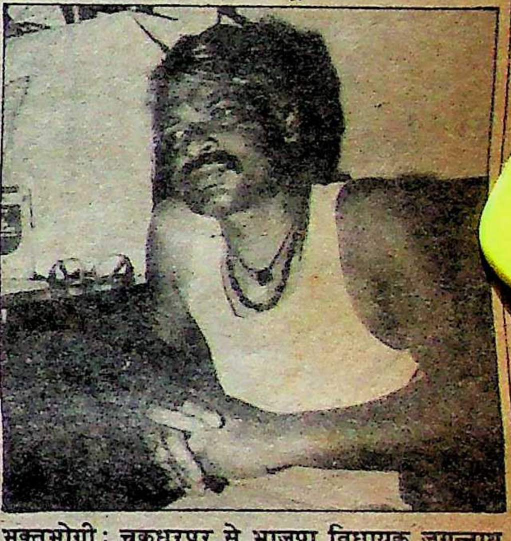
मुक्तभोगी : चक्रधरपुर से भाजपा विधायक जगन्नाथ

चिरीबुरु खान में क्वार्टजाइट खनिज का इस्तेमाल उच्च सिलिका के साथ सिलिका-ईंट उत्पादन में किया जाता है। पहले उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड इसके जरिये विदेशी मुद्रा अर्जित करता था। चिरीबुरु और इसके पास के दो पहाड़ों में क्वाटजाइट का अकूत भंडार है। पर इसके बावजूद यहां के लोग भूख से मरने को विवश हैं। इसी तरह सिंहभूम के तकरीबन २० चूना-पत्थर खदानों में कार्यरत छह-सात मजदूरों में आधे से अधिक आदिवासी औरतें हैं जिनके संग हो रहा शोषण भयानक है। इन खदानों में एक मजदूरिन दिनभर में दो-ढाई रुपए से अधिक मजदूरी नहीं हासिल कर पाती। ऐसे में बाहर के ठेकेदार अधिक मजदूरी का लालच देने आते हैं और फिर नतीजा-वही अंधी गली।

आदिवासी महिलाओं में जाग्रतिः पुर्णेन्दु के संग इस इलाके में सक्रिय लारो जोंको चिरीबुरु खदान की बंदी को लेकर उभरे संघर्ष में जो आगे आयी सो आजतक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईचाकुटी गांव की युवती लारो जोंको १९८३ में बल्गेरिया आदि भी जा चुकी है। चक्रधरपुर के इस जंगली इलाके में लारो एक ऐसी उत्साही और जुझारू औरत है, जिसमें कैसे भी बुरे हालात से टकराने का माद्दा है, इसलिए पुर्णेन्दु मजूमदार को भी लगता है कि वह अकेले नहीं हैं। पुर्णेन्दु और लारो ने मिलकर पहाड़ से घिरे इन आदिवासी गांवों में चेतना की मुनादी कर दी है। इसका असर भी तेजी से

७० सेकंड की चाबी

खजाना खोलेगी

पूरी ताकत का! पूरी शक्ति का

बुलवर्कर- 3 की बदौलत दुनिया भर में लाखों लोगों ने कामयाबी हासिल की है. अब आप भी ताकत बढ़ानेवाले इस जगप्रसिद्ध कामयाब तरीके आज़मा सकते हैं–वो भी मुफ्त! ये है रोजाना 70 सेकंड के जोरदार आइसोटोनिक/आइसोमेट्रिक वर्जिश प्रोग्राम–एक ऐसी आजमायी हुई चाबी जो आप के लिए शक्ति का खजाना खोल देगी . . . आपको मनचाही ताकतवर 'सुपरबॉडी' देगी.

आदम कद शीशे के सामने खड़े होकर, अपनी शारीरिक अवस्था के बारे में खुद भ्रम में पड़ जाना कितना सरल है. क्या सचमुच आपका शरीर वैसा ही मर्दाना है जिससे दूसरे पुरुषों में ईर्ष्या जाग उठे और स्त्रियों में प्रशंसा? अगर नही तो यह खबर सुन कर आप झूम उठेंगे? एक अति क्रांतिकारी, नए किस्म का साधन बनाया गया है जो आपको वैसा ही बदन देगा जैसा आप हमेशा से चाहते रहे है और वह भी सिर्फ कुछ सप्ताहों में ही! इस नए साधन का नाम है बुलवर्कर– 3. कल्पना कीजिए . . . आपकी मॉस पेशियाँ फौलादी हों . . . बाहों की मछलियों का शक्तिशाली मर्दाना उभार . . . पेड़ के प्रचंड तने जैसी रानें. अब आप इसे हकीकत बना सकते है. और आप स्वयं यह केवल 14 दिनों में सिद्ध कर सकते है!

शारीरिक गठन में निपुण लोग बताते है कि किस तरह ये व्यायाम आपको पर्याप्त शक्तिशाली शरीर दे सकते है!

ये है लेन सेल, भूतपूर्व मिस्टर युनिवर्स, 7 सेकेंड की आसान बुलवर्कर व्यायाम श्रेणी करते हुए

यह व्यायाम गहरा सुगठित मर्दाना सीना बनाता है

ये देखिए आप किस तरह आकर्षक सुगठित शरीर का 'V' आकार प्राप्त कर सकते है

यह व्यायाम पीठ की मॉस-पेशियाँ सुगठित कर आपको स्फूर्तिभरे पुरुष का रूप देता है

यह आपके हाथों में नई शक्ति भरता है

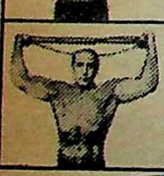

ये देखिए आप किस तरह गठित मांस-पेशियों वाले कंधे बना सकते है

अंतर्गत पॉवरमीटर

से आप अपनी मांस पेशियों की शक्ति को दिन-ब-दिन बढ़ते हुए देख सकते है.

3 साल की गारंटी

साथमें

- ●बुलवर्कर रखनेका आवरण
- ●२४ पृष्ठों की सचित्र पुस्तिका
- ●दीवार पर लगाने के लिए सौदाहरण व्यायाम तालिका.
- ●आहार और शिक्षण गाईड.

ABHA

खेल के सामान की सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध

कृपया ध्यान दें कि वी पी पी. से आर्डर देने पर वी पी पी खर्च का भुगतान सीधे पोस्ट आफिस को देना होगा

घटी कीमत में

सामान्य रिटेल कीमत रु. 325/-

अब आपके लिए सिर्फ रु. 298/- में

अगर आप 30 दिन में जवाब दें

वी पी पी द्वारा इस पते से मंगा सकत है:
बुलवर्कर प्रा. लि.
मेहता महल, 15 मैथ्यू रोड,
बम्बई 400 004.

यह कूपन आज ही भेजिए

बुलवर्कर प्रा. लि. 15 मैथ्यू रोड, बम्बई–400 004. 539-R LO

कृपया 14 दिनों की आजमाइश के अन्तर्गत मेरा बुलवर्कर–3 मुफ्त उपहार के साथ भेज दीजिए. यदि मैं पूर्णतया परिणामों से सन्तुष्ट नही हुआ तो आजमाइश अवधि के अन्दर अपनी रकम (डाक व अतिरिक्त खर्च काटकर) वापिस पाने के लिए शीघ्र ही सबकुछ लौटा दूँगा. MY·56

कृपया उचित चौकोर में ☑ निशान लगाइए

☐ रजि. पोस्ट पार्सल द्वारा भेज दीजिए. मैं रु. 298/-का ड्रॉफ्ट/आइ.पी.ओ. मनीऑर्डर नं.............. तारीख...................... (देय बुलवर्कर प्रा.लि. के नाम) भेज रहा हूँ.

☐ वी.पी.पी. द्वारा भेज दीजिए. डिलीवरी के समय डाकिए को रु. 298/- देने का वचन देता हूँ.

नाम: ....

पता: ....

....

पिन: .... हस्ताक्षर ....

हो रहा है। लारो भी बारह वर्ष की उम्र से ईंट-भट्ठों में मजदूरी करने जाती थी। वह कमरगच्छी के ईंट-भट्ठों में अर्से तक काम करती रही। इसलिए वह जानती है ईंट-भट्ठों में चालू दैहिक शोषण की संस्कृति को। लारो 'महिला समाज' नामक एक संगठन भी चलाती है, जिसकी वह अध्यक्ष है। उसने 'माया' को बताया कि 'महिला समाज' के जरिए आदिवासी औरतों को जागृत किया जा रहा है। डायन करार कर जिस तरह आदिवासी औरतें मारी जा रही हैं, हम इस अंध-विश्वास को मिटाने में लगे हैं। लारो कम्युनिस्ट पार्टी की मजदूर इकाई ए० आइ० टी० यू० एस० से सम्बद्ध है और खरसावां विधान सभा क्षेत्र से दो बार चुनाव भी लड़ चुकी है। लेकिन थोड़े मतों से वह दोनों बार हार गयी। पुर्णेन्दु भी पूर्णकालिक ए० आइ० टी० यू० सी० के कार्यकर्ता हैं। वह अविवाहित हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जंगल के इन लोगों के लिए समर्पित कर चुका हूं। मैं इन्हीं के बीच काम करते-करते मरना चाहता हूं। लारो जोंको भी अविवाहित हैं और वह कहती है कि विवाह करने पर उसकी सामाजिक गतिविधियां शिथिल पड़ सकती है। इसलिए वह शादी नही करेगी। पुर्णेन्दु कहते हैं, "ईंट-भट्ठों में आदिवासी मजदूरिनों की बिक्री व दैहिक शोषण के बारे में उन्होंने सरकार से लेकर कई स्वयंसेवी संगठनों को भी लिखा, पर आजतक कुछ भी नहीं हुआ।"

चक्रधरपुर सबडिविजन के ही कोटासोना गांव की मांदुई होनाहागा नामक आदिवासी युवती जो कुछ साल पूर्व 'आदिवासी महिला समाज' की अध्यक्ष थी, आदिवासी लड़कियों के शोषण को लेकर काफी उत्तेजित हैं। मांदुई कहती है, "जंगल के हमारे खदानों पर बाहरी ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया और हमारे मर्द बेकाम कर दिये गये। हम औरतों को ये गैरआदिवासी दिक्कू ठेकेदार बेच रहे हैं और हमारे पेट में अपना बच्चा डाल रहे हैं। आदिवासी औरतों के पेट से दुश्मन के बच्चे जन्म ले रहे हैं। यह साजिश है। गहरी साजिश। सच्ची आदिवासी औरत वही होगी जो अपनी कोख से जने दुश्मन के बच्चे का खुद अपने हाथों से गला घोंट दे।" कहते-कहते मांदुई बेतरह विचलित हो उठती है।

सचमुच मादुई का सुर्ख चेहरा और सोम्बारी के दर्द से सीझे चेहरे में फर्क है। पर कौन सा फर्क? मांदुई जो 'दिक्कू' यानी दुश्मन के बच्चे को अपने पेट में पलने देने के खिलाफ मुट्ठी ताने है और सोम्बारी जो एक मां है। सोमा की मां। सोमा यानी दुश्मन का बच्चा! कैसे मारे वह उसे! अपने ही रक्त से तो बना है, उसका शरीर! फिर सोमा की निश्छल आंखों में दुश्मन की आंखों जैसा हिंसा का कोई भाव भी तो नहीं!

ईंट-भट्ठे के साये में उपजे ये बच्चे किस घर की ईंट बनेंगे? लारो जोंको अफसोस के साथ उसांसे भर कर कहती हैं, "दुश्मन के बेटे इन पहाड़ों के बीच पलबढ़कर अपने उन्हीं नाजायज बापों के खिलाफ तीर उठायेंगे....जरूर उठायेंगे।" ■

> *"जंगल के हमारे खदानों पर बाहरी ठेकेदारो ने कब्जा कर लिया और हमारे मर्द बेकाम कर दिये गये। हम औरतों को ये गैरआदिवासी दिक्कू ठेकेदार बेच रहे हैं और हमारे पेट में अपना बच्चा डाल रहे हैं। आदिवासी औरतों के पेट से दुश्मन के बच्चे जन्म ले रहे हैं। यह साजिश है। गहरी साजिश। सच्ची आदिवासी औरत वही होगी जो अपनी कोख से जने दुश्मन के बच्चे का खुद अपने हाथों से गला घोंट दे।"*

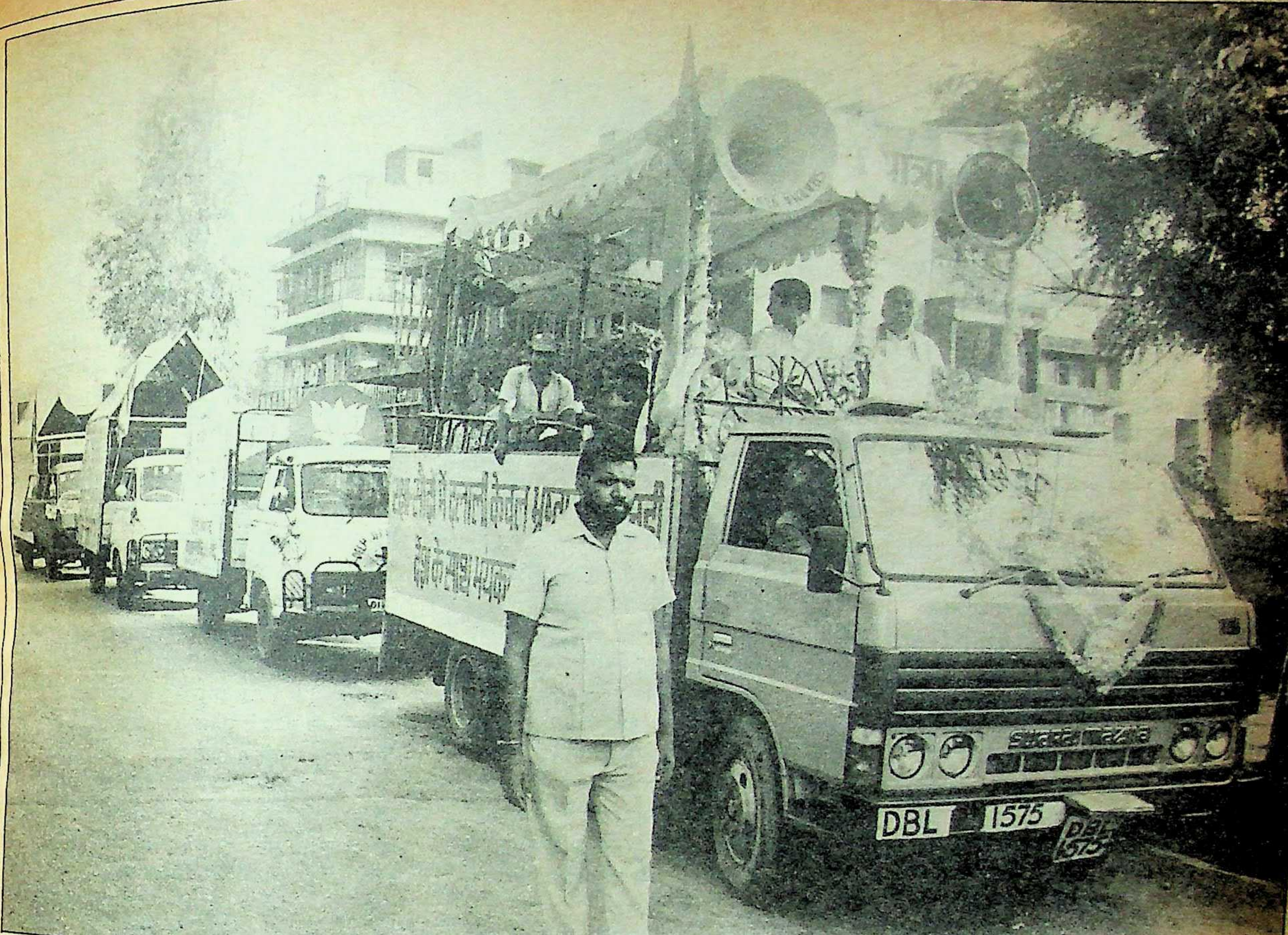

चुनावी युद्ध का नगाड़ा : भाजपा की न्याय-यात्रा

चुनाव की दस्तक

भाजपा की 'न्याय-यात्रा' और 'न्याय युद्ध' का दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ा है ? क्या भाजपा के आक्रामक रुख को देखते हुए दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर-निगम के चुनावों के खिसकने की संभावना है ? भाजपा की रणनीति को विफल करने के लिए इंका के सिपहसालार क्या कर रहे हैं ?

"दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालने की चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। हम इंका को ऐसी कोशिशों के बाबत खबरदार करना चाहते हैं। अगर उसने चुनाव टालने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जबरदस्त विरोध करेगी"—भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने ३१ अगस्त को महरौली में 'न्याय यात्रा' की समाप्ति पर कहा। श्री आडवाणी की यह ललकार अब तक अनसुनी है। श्री आडवाणी की आशंका के मूल में यह अफवाह है कि फरवरी '८८ में दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम की मियाद पूरी हो जाने के बावजूद चुनाव नहीं होंगे। ऐसी घोषणाएं वक्त के सिर पर सवार होने के बाद ही की जाती हैं, इसलिए चुनाव नहीं होने की घोषणा भी ऐन वक्त पर ही होगी। इसके लिए देशव्यापी सूखे जिसका कुछ असर दिल्ली के देहातों पर भी है, को बहाना बनाया जा सकता है।

न्याय यात्रा और न्याय युद्ध : करीब चार महीने पहले दिल्ली की मतदाता सूचियों के नवीनीकरण को चुनाव के दरवाजे पर दस्तक माना जा रहा था। दक्षिण दिल्ली युवक इंका अध्यक्ष सुभाष शर्मा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण सिह तंवर ने मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़े को लेकर लंबा बयानी युद्ध लड़ा था। इन युद्धों से इंका की चुनाव लड़ने की इच्छाशक्ति का अहसास होता था। पर अब भाजपा की १८ से ३१ अगस्त तक 'न्याय यात्रा' और ७ से १५ सितंबर तक के 'न्याय युद्ध' के बाद नजारे बदले हुए लग रहे हैं। 'न्याय यात्रा' के बाबत दिल्ली इंका की शक्तिशाली तिकड़ी, केन्द्रीय संसदीय कार्य और आपूर्ति मंत्री हरिकिशन लाल भगत व उनके दो भक्तों—मुख्य कार्यकारी पार्षद जग प्रवेश चन्द्र तथा प्रदेश इंका अध्यक्ष ताजदार बाबर ने २० अगस्त को प्रेस कांफ्रेंस की। इसका असर 'न्याय यात्रा' के प्रचार के रूप में ही सामने आया। इन तीनों के दावे और तर्क पत्रकारों

दिल्ली भी दूर नहीं रही वी०पी० सिंह से

डा० एस०सी० वत्स ने १७ सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी—इ के डाक्टर्स सेल के संयोजक पद, दिल्ली प्रदेश इंका के संयुक्त सचिव पद और महानगर परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया—क्योंकि इंका ने न तो चुनावी वायदे पूरे किये, न राजीव गांधी ने डाक्टरों की हड़ताल तुड़वाने के लिए दिये गये आश्वासन पूरे किये।

अख्तर अली ने पटरी और खोमचावालों के पुनर्वास और सर्वे के लिए बनी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया—क्योंकि अफसर उन्हें घास नहीं डालते थे। २४ अगस्त को शिक्षा समिति के अध्यक्ष जगदीश टोकस ने समिति की बैठक तब तक नहीं बुलाने का फैसला किया जब तक भ्रष्टों को समिति से दूर नहीं किया जाता। इनका झगड़ा सीधे अपने नेता दीपचंद बंधु से है। ये दोनों नगर निगम में इंका के पार्षद हैं। तीसरे पार्षद जगदीश आनंद दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के अध्यक्ष रामजी लाल पर भ्रष्टाचार के धुआंधार आरोप लगा रहे हैं—फिटकरी खरीद के मामले में। दिल्ली नगर निगम का यह नजारा इंका की खस्ता हालत को दर्शाता है।

कलह का घर बन चुकी दिल्ली इंका में अब दरार बढ़ने लगी है। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चला तो इंका से निष्कासित पूर्व केन्द्रीय पर्यटन मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में इंका में विधिवत बगावत हो जायेगी। बगावत की तैयारी कानों-कान चल रही है। महानगर परिषद के पांच सदस्य, दिल्ली नगर निगम के ६ सदस्य, दो पूर्व कार्यकारी पार्षद, ७ पूर्व महानगर परिषद सदस्य, दो पूर्व विधायक, दो ब्लाक पंचायत समिति अध्यक्ष सहित करीब १०० प्रमुख इंका नेता वी०पी० सिंह के पाले में चले जायेंगे। यह दावा इस बगावत के अगुवा इंका के महानगर पार्षद चंद्र अमृत ने किया। उस वक्त उनके साथ एक अन्य महानगर पार्षद हरीराम खत्री भी थे। हालांकि, दोनों ने वी०पी० सिंह के पाले में जाने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही।

बगावत की वजह महज वी०पी० सिंह के मुद्दे होते तो काफी पहले यह सब हो जाना चाहिए था, मगर वजह वी०पी० सिंह ही नहीं हैं। आगामी चुनाव की चिंता भी इन्हें इंका से किनाराकशी के लिए मजबूर कर रही है। कई लोग समझते हैं कि वी०पी० सिंह के मोर्चे का भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन हो सकता है। इससे कई लाभ होंगे। पहला, वी० पी० सिंह की साख और भाजपा के प्रभाव से दुबारा जीत सकते हैं। दूसरा, भाजपा में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का मौका मिल जायेगा और दलबदल नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चाबंदी में शामिल होने से जनता के बीच आधार बनेगा। वी०पी० सिंह के साथ जाने वाले लोगों के स्वर पिछले कुछ समय से तीखे होते जा रहे हैं। मसलन, हरीराम खत्री ने दिल्ली इंका के एकक्षत्र नेता बने हरकिशन लाल भगत के नरेला में हुए समारोह का बायकाट किया। उनके लोगों ने १३ सितंबर को श्री भगत को काले झंडे तक दिखलाए। भगत ने समारोह आधा छोड़ना ही बेहतर समझा। चंद्र अमृत महानगर परिषद के पिछले अधिवेशन में हर मुद्दे पर विपक्ष के ज्यादा करीब और कभी-कभी विपक्ष से ज्यादा आक्रामक दिखे। पूर्व कार्यकारी पार्षद और दिल्ली देहात जिला इंका अध्यक्ष चौधरी हीरा सिंह ने भी भगत जी के समारोह का बायकाट किया था। इसके पहले नांगल देवत के किसान आंदोलन के समय उन्होंने सीधे-सीधे राजीव गांधी पर आरोप लगाये थे।

बगावत के नेता चंद्र अमृत पहले भगतजी के खास रहे हैं। भगतजी की माखनलाल फोतेदार और अरुण नेहरू के मार्फत दिल्ली दरबार में पैठ थी। इस कारण अरुण नेहरू से चंद्र अमृत के भी संबंध रहे हैं। ९ अगस्त को बागी सांसदों के राजघाट पर उपवास के समय भी चंद्र अमृत, अरुण नेहरू से कानाफूसी करते नजर आये थे। दिल्ली इंका में बगावत के पीछे भी अरुण नेहरू ही हैं।

चंद्र अमृत और हरीराम खत्री १४ सितंबर को इस शर्त पर बातचीत के लिए तैयार हुए कि यह सब उनकी २१ सितंबर की बैठक के बाद छपेगा। "वरना सब प्रोग्राम चौपट हो जायेगा"—वह बोले।

मुफ्ती मोहम्मद सईद के यहां बैठक क्यों हो रही है? चंद्र अमृत ने जवाब दिया—"सारे मूल्य राजनीति से गायब हो रहे हैं। देश की रक्षा और एकता जैसे मामलों में नैतिकता नहीं रही। देश के गरीबों का शोषण हो रहा है। उस शोषण को खतम करने के लिए पहले भ्रष्टाचार खतम करना पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग बैठक में विचार करेंगे।" लंबी पृष्ठभूमि के बाद वह कहते हैं कि राजीव गांधी ने भी १९८५ में बंबई शताब्दी समारोह के दौरान सत्ता के दलालों को हटाने की बात कही थी। पर उलटे सत्ता के दलाल बढ़े हैं। दिल्ली के बारे में उनकी चिंता थी—"डीडीए के अफसरान दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं, लेकिन निहित स्वार्थ के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हुई।" श्री अमृत की बगावत के पीछे कार्यकारी परिषद और पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी भी है। "मैं दो साल से भूमि और आवास के मामले में एक ही एजेंसी के बारे में कह रहा हूं, कोई सुनता ही नहीं। कानून है—पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। अफसर पहले कालोनाइजरों से मिलकर अवैध निर्माण करा देते हैं। जब जनता इन्हें खरीद लेती है तो फिर इन्हें अवैध बताकर तुड़वा देते हैं। इन सबके पीछे दोषी कौन है?" प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा—"अभी हरिजनों के पार्क में अवैध रूप से वर्कशाप बन गयी। मैंने १० जुलाई को उन्हें चिट्ठी लिखी। ३० जुलाई को उनके सेक्शन अफसर ने जवाब दिया। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से भ्रष्टाचार कौन मिटायेगा?" वी०पी० सिंह के बारे में चंद्र अमृत ने कहा—"वी०पी० सिंह मंत्री बनकर रह सकते थे, पर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह पद छोड़ा। ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गये हैं कि वे कुछ भी कहने में अपना भला नहीं समझते।"

चंद्र अमृत की योजना सोशलिस्ट फोरम की तरह ही इंका के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ फोरम बनाने की है, नतीजा चाहे जो हो। फिलहाल वह इंका के भीतर 'प्रेशर ग्रुप' बनाना चाहते हैं। इंका के भीतर सक्रिय रहने से उन्हें ज्यादा लोगों के समर्थन की उम्मीद है। उनका कहना है "पिछले चार सालों से दिल्ली वालों के लिए रोजगार के मौके बंद हैं। लेकिन बड़े राजनीतिक, अफसर चोर दरवाजे से तदर्थ आधार पर नियुक्तियां कर लेते हैं। दिल्ली पर्यटन विकास निगम में कितनी भर्ती हुई, कैसे भर्ती हुई—इस घोटाले के बारे में उपराज्यपाल को बताया गया, पर कुछ नहीं हुआ।"

हरीराम खत्री वी०पी० सिंह के पक्ष में अपनी बात साफ-साफ कहते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली भी देश का हिस्सा ही है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का स्थानीय स्तर की राजनीति से भी नाता है। डी०डी०ए० भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जब ऊपर ही भ्रष्टाचार होगा, तो नीचे कौन रोक पायेगा? वी०पी० सिंह के मुद्दे, जनता के मुद्दे हैं। 'हम दिल्ली के लोगों से हुए वायदे पूरे नहीं कर पाये, इसकी वजह भी भ्रष्टाचार ही है।

डा० वत्स भी वी०पी० सिंह के खेमे से ही जुड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इस तरह दिल्ली इंका की दरार चौड़ी होती जा रही है और आखिरकार इससे राजमहल ढह भी सकता है।

—कुमारगिरि

तक के गले नहीं उतरे। अखबारों में कुछ ऐसी फजीहत हुई कि हिम्मत टूटती चली गयी। दूसरी ओर इन तीनों ने भाजपा के खिलाफ जवाबी अभियान चलाने की घोषणा की, जो एक महीने बाद भी अमल में नहीं आ पायी।

विपक्ष का मतलब दिल्ली के संदर्भ में भाजपा ही है। दूसरे किसी में इंका को चुनौती देने का दमखम नहीं है। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी करीब साल भर पहले ही शुरू कर दी थी। उस समय तक दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल एक वर्ष नहीं बढ़ाया गया था और चुनाव फरवरी '८७ में संभावित थे। तब से भाजपा ने अपनी तैयारियों का तार टूटने नहीं दिया है। लगातार धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां होती रही हैं। इस धारावाहिक आंदोलन को भाजपा ने 'न्याय युद्ध' के रूप में चलाया। 'न्याय यात्रा' के नायक और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने अपने काफिले के साथ १४ दिनों में ११०० किलोमीटर लंबी यात्रा की। ४५० सभाएं कीं। नगर निगम के सभी १०० निर्वाचन क्षेत्रों को उन्होंने छुआ। इन १४ दिनों में श्री खुराना को १८ बार सिक्कों से तौला गया। रोज उनके वजन से ज्यादा फूलों के हार उनके गले पड़ते। कुछ हार रुपयों के भी होते थे। उन्हें इन सबसे करीब सवा छह लाख रुपए प्राप्त हुए। भाजपा ने इस दौरान दस लाख से भी ज्यादा लोगों से संपर्क करने का दावा किया है। इसी तरह ७ से १५ सितंबर तक चले 'न्याय युद्ध' में सरकारी कार्यालयों का घेराव करने वाले १२ हजार से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। अंतिम दिन करीब आठ हजार प्रदर्शनकारियों पर ऐतिहासिक लाल किले के पास जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ। करीब एक हजार कार्यकर्ता लाल किले की १५ फुट खाई में या तो गिर गये या गिरा दिये गये।

कुल मिलाकर 'न्याय यात्रा' और 'न्याय युद्ध' को अपने उद्देश्य में सफल माना गया। पार्टी से न केवल नये कार्यकर्ता जुड़े, बल्कि पुराने कार्यकार्यकर्ताओं का जोश भी आसमान छूने लगा। जनता पर 'न्याय यात्रा' के असर की मात्रा को लेकर विवाद हो सकता है, पर इंकाइयों पर पड़े असर के बारे में कोई विवाद नहीं है। इंका के खेमे में इससे घबड़ाहट फैली। शुरू में तो इंका के कार्यकारी पार्षदों—२४ अगस्त को कार्यकारी पार्षद (विकास) प्रेम सिह, २६ अगस्त को कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) कुलानंद भारतीय, २८ अगस्त को मुख्य कार्यकारी पार्षद जग प्रवेश चन्द्र, २ सितम्बर को कार्यकारी पार्षद (स्वास्थ्य) बंसीलाल चौहान ने दनादन प्रेस कांफ्रेंस कर इनका असर पोंछने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिलने पर उन्होंने यह कवायद भी छोड़ दी।

भाजपा की सक्रियता : भाजपा के आंदोलन की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर इंका के प्रति जनमानस में बढ़ती उदासीनता के साथ ही, दिल्ली के स्तर पर कार्यकारी परिषद और अन्य निकायों का नाकारापन भी है। भाजपा ने इस नाकारापन और भ्रष्टाचार का शोर मचाकर जनता को रिझाने से ज्यादा इंका नेताओं को भयभीत किया है। भाजपा के उठाये गये मुद्दों का इंका के पास ठोस जवाब नहीं है। दूसरी ओर जनता की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। जिस प्रकार देवीलाल ने लंबा आंदोलन चलाकर हरियाणा में सत्ता का आखेट किया था, उसी तरह मौजूदा हालात में प्रदेश भाजपा और उसके नेता श्री खुराना दिल्ली में इस करतब को दुहराने की स्थिति में हैं। 'न्याय यात्रा' और 'न्याय युद्ध' इसी कोशिश के हिस्से हैं।

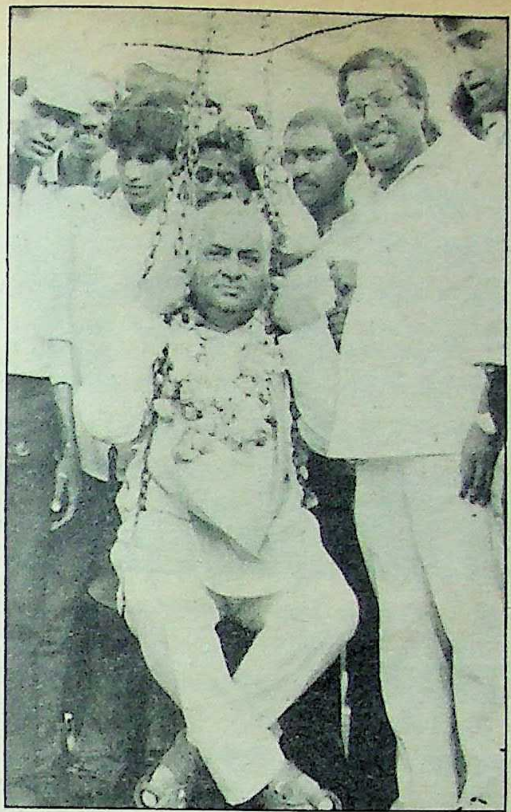

खुराना की चांदी : सिक्कों से तुलते हुए खुराना

भाजपा ने अपने उम्मीदवारों में ७५ फीसदी का चयन तक कर लिया है। उसने चुनाव तक लंबा आंदोलन चलाने की तैयारी भी कर ली है। पहली अक्तूबर से भाजपा प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र से एक लाख रुपए इकट्ठा करने के अभियान में लग रही है। यह एक करोड़ रुपए की थैली भाजपा संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर भेंट की जायेगी। इस क्रम में भाजपा एक ओर जनसंपर्क करेगी, तो दूसरी ओर चुनाव के लिए चंदा जुटायेगी। मदन लाल खुराना प्रचार की रणनीति को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। वह इस मामले में भी देवीलाल के प्रयोग की कार्बन कापी करने की कोशिश में हैं। उन्होंने देवीलाल की तरह 'न्याय युद्ध' का शगूफा छोड़ा। अब वह वीडियो-आडियो प्रचार के लिए सामग्री तैयार करा रहे हैं। इंका की विफलताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भाजपा के संघर्ष को दर्शाने वाली फिल्म के लिए शूटिंग चल रही है। देवीलाल के 'न्याय रथ' और नंदमूरि तारक रामाराव के 'चैतन्य रथम' की तरह श्री खुराना भी रथ तैयार कराने जा रहे हैं। भाजपाई बुद्धिजीवी देवीलाल के 'कर्ज काफी' वाले हिट नारे की तरह कोई नारा ढूंढने में लगे हैं, जिसे भाजपा ट्रंपकार्ड के रूप में चुनाव के एक दो महीने पहले चलेगी—ताकि इंका मुंह ताकती रह जाये।

इंका मुश्किल में : इंका के अंतःपुर का परिदृश्य ठीक उलटा है। चुनाव उनके लिए चुनौती नहीं, चिंता का कारण है। भाजपा आंदोलनों के जरिये जहां कार्यकर्ता जोड़ रही है, वहीं इंका का कलह से भरा संगठन टूटता नजर आ रहा है। इस स्थिति ने स्थानीय स्तर के इंका नेताओं को चिंता में डाल रखा है। भाजपा जहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहां इंका चुनाव टालने की तरकीब भिड़ा रही है। सुना तो यहां तक जाता है कि प्रधानमंत्री आवास पर सितंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के इंका सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव के बारे में संवैधानिक स्थिति पर विचार हुआ। प्रधानमंत्री को बताया गया कि १९८० में इंका की सत्ता में वापसी पर जनता पार्टी की बहुमत वाली महानगर परिषद और नगर निगम को भंग कर दिया गया था। फिर चुनाव तीन साल बाद हुए। नगर निगम का कार्यकाल एक साल बढ़ाया जा चुका है, संविधान उससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता। दूसरी ओर महानगर परिषद के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए यदि अनुकूल स्थिति आने तक दोनों के चुनाव नहीं कराये गये तो दोनों संस्थाएं मियाद पूरी होने पर स्वतः मृत हो जायेंगी। इस बीच गृहमंत्री बूटा सिह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी जा रही है, जो दिल्ली का राजकाज देखेगी। इस कमेटी में इंका के दिल्ली से सभी लोकसभा सदस्य हो सकते हैं।

दिल्ली इंका में किसी भी स्तर पर चुनावी चहल-पहल का शुरू नहीं होना भी इसी संभावना को पुष्ट करता है। हालांकि, इंका के महानगर पार्षद सुभाष चोपड़ा कहते हैं, "हम प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदते। हमने विकास कार्य जारी रखा है। चुनाव में विजय हमारी ही होगी।" पर श्री चोपड़ा का यह बयान दुस्साहस से ज्यादा नहीं है। इंका की हालत भी विचित्र है। ईमानदार लोगों की पार्टी में दुर्गति है। दिल्ली क्लाथ मिल, बाड़ा हिंदूराव को बंद करने से करीब ६००० मजदूर परिवार बेरोजगार हो जायेंगे। राष्ट्रीय टेक्सटाइल्स कांग्रेस के महासचिव चतर सिह ने इस कोशिश के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है,जिसकी सजा उन्हें इंटक से बाहर निकालकर दी गयी है। चुनाव टालने की चर्चा पर चतर सिह ने कहा, "कोई संभावना नहीं। अगर संभावना होती तो प्रदेश इंका ९ सितंबर की बैठक में जनसंपर्क करने का फैसला क्यों करती।" इन्हीं की पार्टी के महानगर पार्षद चन्द्र अमृत का कहना है, "१९८० में भी तीन साल तक चुनाव नहीं कराये गये थे। हमारे बहुत से एम०पी० चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव हुए तो इसका उनके चुनाव पर खराब असर पड़ेगा। इसलिए शायद लोकसभा चुनाव तक चुनाव न कराये जायें।"

कांग्रेस (इ) द्वारा
दिल्ली से घोर विश्वासघात

भाजपा की नजर में इंका

वायदे करायेंगे इंका को आत्महत्या !

'न्याय यात्रा' से लेकर 'न्याय युद्ध' तक में भाजपा ने इंका प्रशासन के दिल्ली की जनता के साथ 'विश्वासघात और अन्याय' को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। दरअसल दिल्ली में प्रशासनिक इकाइयों की भरमार ने दिल्ली की समस्याओं को ज्यादा उलझाया है। दिल्ली न तो अपना बजट खुद पास कर सकती है, न खुद कानून बना सकती है। हर चीज़ के लिए उसे केन्द्र सरकार का मोहताज रहना पड़ता है। यहां तक कि अफसरों की नियुक्ति भी केन्द्र ही करता है। ऐसे में अफसर स्थानीय नेतृत्व को घास नहीं डालते। राष्ट्रीय मुद्दों में उलझे रहने वाले केन्द्रीय नेतृत्व को दिल्ली के लिए वक्त नहीं मिलता। दिल्ली के पिछले मास्टर प्लान की मियाद अक्तूबर, १९८१ में ही पूरी हो चुकी है। अभी तक अगला मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। सिर्फ सड़क बनाने का काम छह एजेंसियां करती हैं। "दिल्ली की समस्याओं का हल तभी हो सकता है, जब दिल्ली का अपना राज हो। यह अपना राज दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ विधानसभा मिलने से हो सकता है" —प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने कहा, जबकि गृहराज्यमंत्री चिंतामणि पाणिग्रही संसद के पिछले सत्र में ही दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने से साफ इनकार कर चुके हैं।

"भाजपा ने अपने आंदोलन में कार्यकारी परिषद की विफलता के साथ ही इंका के अधूरे चुनावी वायदों को मुद्दा बनाया है। यह सही भी है कि १९८३ के चुनाव में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी—इ ने ६ पेज के फोल्डर में जो ३४ वायदे किये थे, उनमें से इक्के-दुक्के भी शायद ही पूरे हुए हों। कुछ वायदे पूरे होना केन्द्रीय नेतृत्व की इच्छा पर है। पर इनमें (इंका नेताओं) हिम्मत ही नहीं है, अपने आकाओं पर दबाव डालने की"—श्री खुराना कहते हैं।

वायदे पूरे न होने की वजह से इंका ने भाजपा के हाथ में विरोध का तेज हथियार ही थमा दिया है जिसे वह कभी न्याय यात्रा के रूप में देखती है, तो कभी न्याय युद्ध में भांजती है। न्याय यात्रा और न्याय युद्ध के जनता पर पड़े असर के बारे में इंका के महानगर पार्षद चन्द्र अमृत की यह राय महत्वपूर्ण है—"जब आदमी दुखी होता है तो आम आदमी यह नहीं देखता कि वह कांग्रेस है, भाजपा है या कम्युनिस्ट है जो उसके दुख की बात करेगा, उससे सहानुभूति जतायेगा—वह उसकी तरफ चला जायेगा। हमारी कमजोरी होगी तो दूसरों का फायदा उठाना स्वाभाविक ही है।" चंद्र अमृत की तरह ही इंका के महानगर पार्षद हरी राम खत्री भी कार्यकारी पार्षद को निकम्मा मानते हैं ?

इंका नेताओं में यह भावना कितनी प्रबल है, इसका पता डा० एस०सी० वत्स के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी—इ के डाक्टर्स सेल के संयोजक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी—इ के संयुक्त सचिव पद और महानगर परिषद की सदस्यता से इस्तीफे से जाहिर है। उन्होंने कहा—"हमने दिल्ली की समस्याओं को लेकर पिछले चुनाव में जनता से वायदे किये थे, उन्हें प्रदेश नेतृत्व की निष्क्रियता और अफसरशाही के हावी होने के कारण पूरा नहीं किया गया। चुनावों से पहले यदि कुछ किया भी जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। दिल्ली को देखने वाले नेता और अफसरशाही मिलकर पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। सब अपने स्वार्थों में लिप्त हैं।"

—कुमारगिरि

वायदे, वायदे रहे : इंका ने अपने १९८३ के चुनाव घोषणा पत्र में ३४ वायदे किये थे। भाजपा के प्रदेश महासचिव मेवा राम आर्य ने कहा, "इनमें से एक वायदा भी पूरा नहीं हुआ। जनता इस ठगी का जवाब चुनाव में देगी।" भाजपा नेता श्री आर्य को इंका नेता चतर सिंह की तरह ही चुनाव टालने की संभावना नजर नहीं आती। "यदि चुनाव टाला गया तो इंका का सत्यानाश हो जायेगा। वे मेरी सूचना के अनुसार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। चुनाव लड़कर वह सम्मान के साथ हार को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं कराया तो जनता का सामना करने से कतराने की उनकी कोशिश देश भर में उनकी बदनामी का सबब होगी। मुझे तो लगता है कि चुनाव वक्त पर होंगे।" चुनावी वायदे पूरे नहीं होने पर असंतुष्ट नेता और दिल्ली इंका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी फतेह सिंह ने कहा, "चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार काम करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों को निर्देश शक्तिशाली प्रदेश अध्यक्ष ही दे सकता था। पर यहां तो प्रदेश अध्यक्ष ही कमजोर है। वैसे हमारी पार्टी ने विकास का काम तो किया ही है।"

चौधरी फतेह सिंह जैसे नेता पार्टी में बने रहने की मजबूरी के कारण बचाव भले ही करें, मगर जिन्हें चुनाव का सामना करना है उनकी हालत पतली है। यही वजह दिल्ली इंका के ढेर सारे नेताओं को विश्वनाथ प्रताप सिंह के खेमे की ओर ले जाने वाली है। 'न्याय यात्रा' १८ अगस्त को शुरु हुई, शायद इसकी सफलता का ही असर था कि २३ अगस्त को इंका के तीन महानगर पार्षदों—चन्द्र अमृत, हरीराम खत्री और वी०पी० खुल्लर ने राजीव गांधी को बच्चन बंधुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दो पेज की कड़ी चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में कानूनी प्रावधानों का ब्यौरा देकर श्री गांधी को बताया गया कि किसी तरह आप बच्चन बंधुओं को जेल की हवा खिला सकते हैं। पत्र के अंत में लिखा था, "जब तक यह कार्रवाइयां नहीं की जातीं अधिकांश जनता मानने लगेगी कि हमारे यहां दो तरह के कानून हैं, एक आम आदमियों के लिए है दूसरा बच्चनों के लिए।" राजीव गांधी ने न तो इस चिट्ठी का जवाब दिया, न ही इंका ने इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत दिखायी।

जब तक 'माया' का यह अंक आपके हाथों में पहुंचेगा, संभव है कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रदेश इंका के पदाधिकारी स्तर तक के करीब १०० नेता वी०पी० सिंह की शरण में चले जायें।

कुल मिलाकर प्रचार की पहल तो भाजपा के हाथों में ही है। पर कई यक्ष प्रश्न अभी हैं। क्या चुनाव वक्त पर होंगे ? अगर चुनाव हुए तो क्या हालात भी अभी जैसे ही होंगे ? फिलहाल चुनाव पूर्व युद्धाभ्यास जारी है और इस युद्धाभ्यास के दौरान इंका के हौसले पस्त हैं।

—कुमारगिरि

बोफोर्स चीफ मोरबर्ग की भारत यात्रा

रहस्य और गहराया

पूरा देश आज यह जानने को बेताब है कि बोफोर्स तोपों की खरीदी में दलाली खानेवाले लोग कौन हैं ? बड़ी उम्मीद बंधी थी कि बोफोर्स के अध्यक्ष मोरबर्ग की भारत यात्रा से इन दलालों के नामों का पता चल जायेगा । वह आये, लेकिन किसी का नाम बताये बिना रहस्य को और गहरा करके चले गये । आखिर मोरबर्ग की भारत यात्रा का असली मकसद क्या था ? गृहमंत्री बूटासिंह दलालों के नाम जानने के बजाय, उनसे यह क्यों कहलवाना चाहते थे कि राजीव गांधी ने दलाली नहीं खायी है ? अपने देश में धोखाधड़ी के मुकदमों में फंसी हथियारों की एक बदनाम कंपनी के मुखिया से भारत के प्रधानमंत्री के लिए ईमानदारी का प्रमाणपत्र मांगना क्या राष्ट्र का अपमान नहीं है ?

"बोफोर्स ने हमें इतनी बार गुमराह किया है कि अब हम इस पर और अधिक विश्वास नहीं कर सकते कि वे जो कहते हैं, उसे कैसे साबित कर रहे हैं।"

—भूपतराय ओझा
स्वीडन में भारतीय राजदूत, १ सितम्बर, १९८७

बोफोर्स की विश्वसनीयता पर स्वीडन स्थित भारतीय राजदूत द्वारा की गयी उक्त टिप्पणी के १२ दिनों बाद बोफोर्स के अध्यक्ष मोरबर्ग और उपाध्यक्ष एवं मुख्य कानूनी सलाहकार गोथलिन दिल्ली पहुंचे और मौर्या शेरेटन होटल में रुके। वे वहां जिस गोपनीय ढंग से रहे वह आश्चर्यजनक था, लेकिन इससे भी अधिक आश्चंर्यजनक था, उनका दो दिनों तक नार्थ ब्लाक में भारतीय अधिकारियों से विचार-विमर्श, क्योंकि इसी के बाद यह घोषणा हुई कि बी० शंकरानंद की अध्यक्षता में बोफोर्स-दलाली के मामले की जांच कर रही संसदीय समिति के सामने बोफोर्स के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित होंगे। न्याय विधान के सारे नियमों और नैतिकता को ताक पर रखकर कठघरे में खड़े होने के पूर्व अभियुक्त अभियोजक से परामर्श कर रहा था। मोरबर्ग की इस यात्रा पर सुरक्षा मंत्री के०सी० पंत ने टिप्पणी की थी कि उनकी यह यात्रा विपक्षियों के इस आरोप को ध्वस्त कर देगी कि भारत सरकार दिल्ली में बोफोर्स के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में हिचकिचा रही है, लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों को विश्वास हुआ था। भारतीय राजदूत की टिप्पणी और पूर्व में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आनेवाले बोफोर्स अधिकारियों की यात्रा को बेमतलब बताकर रद्द कर दिये जाने से बोफोर्स की विश्वसनीयता पर संदेह और गहरा तो हो ही गया था, लेकिन एक पत्रकार वार्ता में बोफोर्स से मिले 'पाक-साफ होने के प्रमाण पत्र' का वाचन करने से ये सब बातें अमिताभ बच्चन को विचलित नहीं कर सकीं। और-तो-और गृहमंत्री बूटा सिंह भी बोफोर्स के अधिकारियों से प्रधानमंत्री के लिए 'पाक-साफ होने का प्रमाण पत्र' प्राप्त करने से खुद को नहीं रोक सके।

जले पर नमक : बताया जाता है कि संसदीय जांच समिति के सामने बूटा सिंह ने मोरबर्ग से पूछा था कि क्या बोफोर्स ने प्रधानमंत्री और उनके परिवार को कोई भुगतान किया है ? मधु दंडवते के अनुसार यह ऐसा ही था मानो अपराधी से गवाही देने के लिए कहा जा रहा हो। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था, "यह ध्यान देने योग्य बात है कि राजीव गांधी ने बोफोर्स को अपना प्रतिनिधि दल भेजने से रोक दिया था, क्योंकि उसने लिखित जानकारियां देने से इनकार किया था।" लेकिन वे आये भी तो उन्हें मौखिक वक्तव्य देकर जाने दिया गया। वाजपेयी के अनुसार, वे जले पर नमक छिड़क कर चले गये।

यह रहस्यमय है कि भारत सरकार बोफोर्स हथियारों की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है, इसके बावजूद वह बोफोर्स पर दलाली के मामले में राजीव गांधी को पाक-साफ करने का कोई दबाव नहीं डाल सकी। स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही नहीं, बल्कि संसद की सर्वोच्चता का भी अपमान हथियारों के एक सौदागर को करने की अनुमति दे दी। यह भी खेदजनक है कि सांसदों ने भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की कीमत पर यह अपमान होने दिया।

वास्तव में जिन परिस्थितियों में बोफोर्स के अधिकारी आये और जिस तरह पांच दिन दिल्ली में रुके, उससे सवालों के उत्तर कम मिलते हैं, बल्कि सवाल कहीं ज्यादा खड़े होते हैं। बोफोर्स अधिकारियों के आगमन की घोषणा ही रहस्यपूर्ण है। १३ सितंबर को भारतीय समाचार पत्रों ने स्वीडन टेलिविजन के हवाले से खबर छापी कि बोफोर्स के अध्यक्ष मोरबर्ग 'कुछ ही दिनों में' भारत आनेवाले हैं। दूसरे दिन उनकी यात्रा के संबंध में कोई खबर नहीं थी, लेकिन अखबार वाले यह जानकर चौंक उठे कि उसी दिन मोरबर्ग अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। संयोगवश उसी दिन प्रधानमंत्री सचिवालय ने घोषणा की कि राजीव गांधी उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अपना निर्धारित दौरा स्थगित कर रहे हैं। यह ऐसा निर्णय था, जिसकी विपक्षियों द्वारा अच्छी-खासी आलोचना हुई।

यात्रा-विवरण : आगे की घटनाएं मोरबर्ग की यात्रा को और भी रहस्यमय बना देती हैं। पहले दो दिन मोरबर्ग की सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से गहरी बातचीत हुई। चूंकि प्रेस को दोनों पक्षों ने दूर रखा इसलिए यह बात जाहिर नहीं हो सकी कि इस बातचीत का विषय क्या था। वस्तुस्थिति तो यह थी कि प्रेसवालों को उनके मौर्या शेरेटन होटल में ठहरने के सिवाय अन्य किसी बात की, यहां तक कि उनके हुलिए तक की जानकारी नहीं थी। प्रेस को जानबूझकर दूर रखा गया। छात्रों और विपक्षी पार्टियों के करीब दो सौ कार्य-

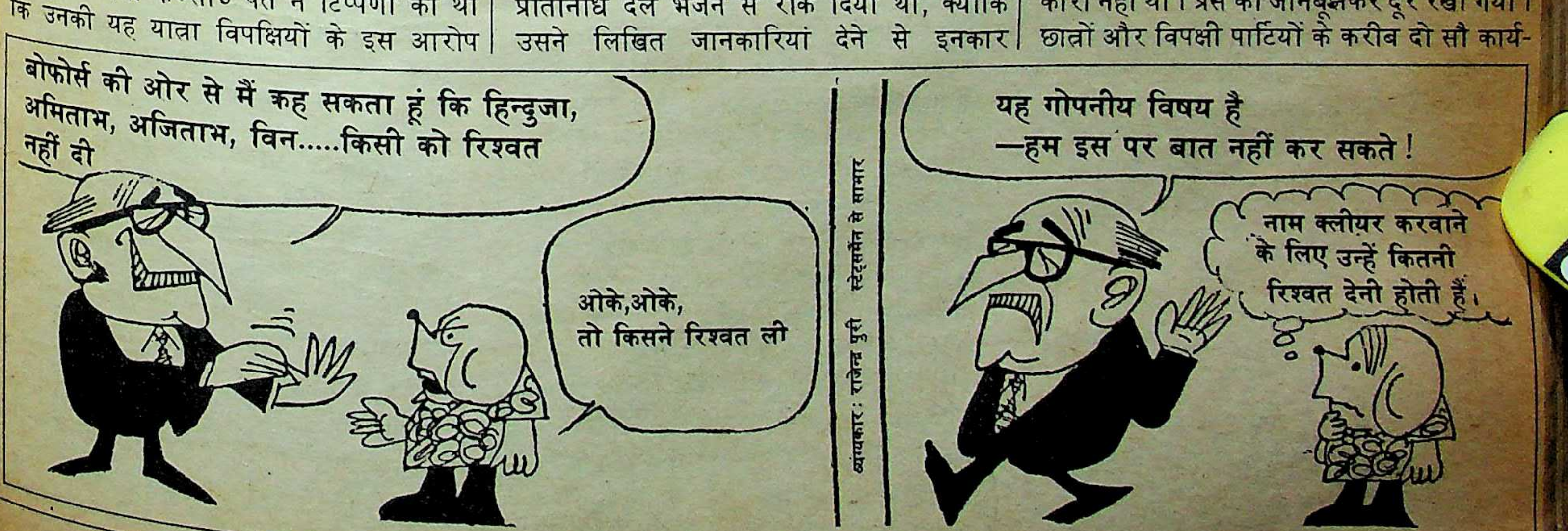
बोफोर्स की ओर से मैं कह सकता हूं कि हिन्दुजा, अमिताभ, अजिताभ, विन.....किसी को रिश्वत नहीं दी
ओके,ओके, तो किसने रिश्वत ली
यह गोपनीय विषय है —हम इस पर बात नहीं कर सकते !
नाम क्लीयर करवाने के लिए उन्हें कितनी रिश्वत देनी होती है।

व्यंग्यकार: राजेन्द्र पुरी स्टेट्समैन से साभार

बोफोर्स के काले कारनामे

भारत सरकार ने जब १ अप्रैल, १९८६ को स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से १७०० करोड़ रुपए की कीमत में ४१० मैदानी तोपों का सौदा किया था, तब तक यह कंपनी अपने ही देश के कानूनों को तोड़ने के कारण काफी बदनाम हो चुकी थी। हालात खुद संकेत देते हैं कि ऐसी बदनाम कंपनी से उस वक्त सौदा करनेवाले संदेह से परे नहीं हैं।

दुनिया की सबसे पुरानी शांति संस्था—स्वीडिश पीस ऐंड आरबीट्रेसन सोसायटी के अध्यक्ष अंगस्ट्राम ने मई, १९८४ में ही स्टाकहोम पुलिस को सूचित कर दिया था कि बोफोर्स कंपनी शांति के लिए खतरनाक घोषित और स्वीडन सरकार की काली सूची में दर्ज देशों को हथियार बेच रही है।

अंगस्ट्राम और शोधकर्ता हेनरिक वेस्टेंडर ने प्रमाणों के साथ बताया कि बोफोर्स ने १९७९-८० में बहरीन और दुबई को जमीन से हवा में मार करनेवाली मिसाइलें—आर०पी०एस०-७० बेची हैं। उल्लेखनीय है कि ये दोनों मुल्क स्वीडन सरकार की काली सूची में दर्ज हैं और जब १९७८ में बोफोर्स ने इन मुल्कों को एक करोड़ डालर की ऐसी ३०४ मिसाइलें बेचने की अनुमति मांगी थी, तो स्वीडन सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया था।

वेस्टेंडर ने अनेक वर्षों की खोजबीन के बाद यह सिद्ध कर दिया कि इन मिसाइलों को अरब मुल्कों को बेचने के लिए बोफोर्स ने सिंगापुर के नाम से लायसेंस लिये। १९७९ और उसके बाद सिंगापुर बोफोर्स से सर्वाधिक हथियार खरीदनेवाला मुल्क बन गया था। अकेले १९७९ में ही उसने २७० लाख डालर के हथियार बोफोर्स से खरीदे थे। बाद में पता चला कि जमीन से हवा में मार करनेवाली ये आर०बी०एस०-७० मिसाइलें खाड़ी के देशों में विमानों पर मार कर रही हैं और अधिकतर ईरान में तैनात हैं।

भंडाफोड़ : अक्तूबर, १९८४ में पं० ज़र्मनी के कस्टम अधिकारियों द्वारा स्वीडन के कस्टम अधिकारियों को भेजे गये एक संदेश से बोफोर्स कंपनी द्वारा की जा रही एक और बड़ी जालसाजी का अचानक भंडाफोड़ हो गया। पं जर्मनी के कस्टम अधिकारियों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा था कि बोफोर्स कंपनी के आस्ट्रिया के लिए प० जर्मनी से होकर जा रहे विस्फोटकों से भरे दो रेल-वेगन जब प० जर्मनी के आस्ट्रिया की सीमा से लगे शहर पस्साऊ पहुंचे, तो वहां से वे आस्ट्रिया नहीं गये, बल्कि कुछ दिनों बाद उन्हें प० जर्मनी के एक बंदरगाह हेम्बर्ग की ओर रवाना कर दिया गया, जहां वे सीरिया जानेवाले एक जहाज पर लाद दिये गये। यह संदेश पढ़कर स्वीडन के कस्टम क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन डिवीजन के प्रमुख हंस जानसन चौंक उठे। बोफोर्स आस्ट्रिया के जाली नाम से विस्फोटकों को क्या किसी तीसरे मुल्क को बेच रहा है? यह संदेह पैदा होते ही जानसन बोफोर्स के कार्यालय में अचानक जा धमके। वहां उनके हाथ कुछ चौंकानेवाले दस्तावेज लगे। मसलन, परमिट तो विस्फोटकों को आस्ट्रिया भेजने का था, लेकिन हिदायत यह दी गयी थी कि विस्फोटकों को २५ प्रतिशत पानी मिलाकर भेजा जाये। ऐसा अकसर तब किया जाता है, जब विस्फोटकों को जहाज द्वारा काफी दूर भेजना हो। लेकिन आस्ट्रिया तो इतनी दूर नहीं है और वहां सामान रेल मार्ग से भेजा जाता है। यह सूत्र मिलने के बाद जानसन सक्रिय हो उठे। १९८५ में बोफोर्स कार्यालय पर कस्टम विभाग ने दो दर्जन बार छापे मार कर इतने कागजात जब्त किये कि एक बड़ा कमरा भर गया। कस्टम विभाग के जांच अधिकारी टोर बजोर्न ने बताया कि उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चलता है हथियार और विस्फोटकों का लदान, ईरान, मिस्त्र, सीरिया, बर्मा और इराक जाने वाले जहाजों में हुआ था जबकि परमिट पश्चिमी यूरोप के किसी देश के नाम से होता था। उल्लेखनीय है कि उक्त सारे देशों को स्वीडन से हथियारों का निर्यात करने पर पाबंदी है।

स्वीडन के कस्टम विभाग ने बोफोर्स के खिलाफ सात हजार पृष्ठों का एक आरोप पत्र स्वीडन के सरकारी अभियोजक के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया है, जिसमें १२० लाख डालर के हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के दस प्रतिनिधि आरोप बोफोर्स पर लगाये गये हैं। स्वीडन के कस्टम विभाग ने एक काम और किया। उसने बड़ी मुस्तैदी से ऐसी नाकेबंदी की कि बोफोर्स करीब १२० लाख डालर कीमत के विस्फोटक और हथियार इन मुल्कों को रवाना नहीं कर सका।

एक भेंटवार्ता में जानसन ने बोफोर्स द्वारा विस्फोटकों की तस्करी का एक और रोचक उदाहरण बताया। १९८४ में ईरान सरकार ने 'स्कैंडैनेवियन कमोडिटीज' कंपनी को ४७०० टन बारूद सप्लाई करने का आर्डर दिया था। इस कंपनी के मालिक स्वीडिश व्यापारी कार्ल-एरिक स्मिड्ज ने तब इतनी भारी मात्रा में बारूद की व्यवस्था करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका की कंपनी से संपर्क किया। उसने बोफोर्स से भी सहायता मांगी। ईरान स्वीडन की प्रतिबंधित सूची में दर्ज है, लेकिन युगोस्लाविया को स्वीडन से बारूद का निर्यात किया जा सकता है। बस बोफोर्स के मार्केटिंग निदेशक मार्टिन आर्डबो युगोस्लाविया जा पहुंचे और उन्होंने युगोस्लाविया के राज्य व्यापार संगठन एफ०डी०एस०पी० के अधिकारियों को पटाकर उनसे १४० लाख डालर कीमत के १३०० टन बारूद का आर्डर प्राप्त कर लिया। तब बोफोर्स ने झटपट १३०० टन बारूद की व्यवस्था कर उसे युगोस्लाविया रवाना कर दिया। युगोस्लाविया की कंपनी ने तत्काल यह बारूद स्मिडज को बेंचा—जिसने उसे ईरान पहुंचा दिया।

सरकारी अधिकारी की हत्या : बोफोर्स कंपनी को १८८० में डायनामाइट के अन्वेषक और नोबल पुरस्कार के प्रणेता अल्फ्रेड नोबल ने खरीद लिया था। उनकी अपनी कंपनी 'नोबल केमी' थी। तभी से बोफोर्स और नोबल केमी अलग-अलग नामों से एक कंपनी के रूप में कार्यरत थीं। १९८० में एरिक पेंसनर ने इन दोनों कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया और १९८४ में एक तीसरी कंपनी नोबल इंडस्ट्रीज के नाम से खड़ी की। जनवरी, १९८५ में उसने स्वीडिश व्यवसायी एण्डर्स कार्ल्सबर्ग को इसका अध्यक्ष बनाया। कार्ल्सबर्ग के अधीन बोफोर्स और नोबल की भी कंपनियां थीं। तब तक बोफोर्स के घपले स्वीडिश सरकार की नजर में आ चुके थे। १९८६ में तो बोफोर्स पर अनेक छापे पड़े। बोफोर्स के खिलाफ मुख्य शस्त्र निरीक्षक अल्गरनान मुख्य भूमिका निभा रहे थे। कार्ल्सबर्ग परेशान थे कि बोफोर्स को आरोपों से कैसे बचाया जाये। कहा जाता है कि जनवरी, १९८७ के शुरू में एक दिन कार्ल्सबर्ग ने बोफोर्स के नवनियुक्त अध्यक्ष आर्डबो से गहन विचार-विमर्श किया और उसके बाद वह शस्त्र निरीक्षक अल्गरनान से मिले। अगले दिन अल्गरनान स्टाकहोम रेलवे स्टेशन पर रेल से कटकर मरे पाये गये। अनेक प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि उन्हें प्लेटफार्म पर आती रेलगाड़ी के सामने किसी ने धकेल दिया था।

शस्त्र निरीक्षक अल्गरनान ही नहीं स्वयं स्वीडिश प्रधानमंत्री ओल्फ पाल्मे की हत्या के पीछे भी बोफोर्स कंपनी के अवैध सौदों का हाथ बताया जा रहा है। बहरहाल, स्वीडिश न्यायालयों में बोफोर्स के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। बोफोर्स चीफ आर्डबो को कम्पनी ने बरखास्त कर दिया है। बोफोर्स के अनेक अधिकारियों पर हथियारों की तस्करी के अनेक आरोप हैं। स्वीडिश सरकार की निगाह में बोफोर्स अविश्वसनीय साबित हो चुकी है। स्वीडन के विदेश मंत्री एंडरसन ने स्वीकार किया है कि जांच और नियंत्रण की अवहेलना करने के कारण बोफोर्स हथियारों की तस्करी करने में सफल हो गया, लेकिन अब कानून और कड़े किये जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि अब सरकारी बिक्री के बारे में स्वीडिश कंपनी के बजाय सरकार ग्राहक से पूछताछ को नरजीह देगी। ■

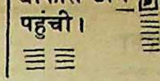

कर्ता जब होटल पहुंचे, तो उन्हें मोरबर्ग से मिलने नहीं दिया गया। हां यह जरूर हुआ कि उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़े।

१६ सितंबर को सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाटकीय घोषणा की कि स्वीडन की टीम ने जो कल वापस जानेवाली थी, अब यहां रुकने की अवधि बढ़ा दी है और अब वह बोफोर्स तोप-सौदों की दलाली के मामले की जांच कर रही संसदीय जांच समिति के सामने उपस्थित होगी। रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा से यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि साउथ ब्लाक में गत दो दिनों तक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से हुई मोरबर्ग और उनके साथियों की बातचीत का मकसद उन्हें यह बतलाना था कि वे जांच समिति के सामने क्या कहें? चूंकि संसदीय जांच समिति में विपक्ष का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह समिति मोरबर्ग से दलालों का नाम जानने में कामयाब हो सकेगी। संसदीय जांच समिति के एक सदस्य ने अपना नाम गुप्त रखे जाने की शर्त पर यहां तक बताया कि जांच समिति ने इस जिरह के लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी और यदि इस समिति में विपक्षी नेता होते, तो संभवत: मोरबर्ग समिति के सामने उपस्थित ही नहीं होते।

दो रहस्योद्‌घाटन : बहरहाल, मोरबर्ग ने संसदीय जांच समिति के सामने दो महत्वपूर्ण रहस्योद्‌घाटन किये। पहला, यह कि उसने भारत के बाहर की तीन अंतरर्राष्ट्रीय कंपनियों को काम समेटने के मुआवजे के रूप में ३१९० लाख क्रोनर (स्वीडिश मुद्रा—करीब ६० करोड़ रुपए) का भुगतान किया है। लेकिन मोरबर्ग ने इन कंपनियों के नाम और मुआवजा लेनेवाले लोगों के नाम बताने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बोफोर्स ने इन कंपनियों के नाम भारत सरकार को बता दिये हैं, लेकिन वह इन कंपनियों के लोगों के नाम व्यावसायिक-गोपनीयता के कारण नहीं बतायेगी। यह जानकारी नयी थी। पहले यह बताया गया था कि काम समेटने का मुआवजा २४०० लाख क्रोनर (करीब ५० करोड़ रुपए) दिया गया है। भारत सरकार के सामने पहली बार आधिकारिक रूप में यह तथ्य आया कि इस मामले से तीन कंपनियां संबद्ध हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण रहस्योद्‌घाटन मोरबर्ग ने यह किया कि बोफोर्स आम तौर पर रक्षा सौदों में १२ प्रतिशत कमीशन देता है। इस आधार पर तोपों के हुए १७०० करोड़ रुपए के सौदे की दलाली २०४ करोड़ रुपए होती है। लेकिन संभवत: इस सौदे में इतनी अधिक दलाली न दी गयी हो, क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि राजीव गांधी और स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे (जिनकी बाद में हत्या हो गयी) के बीच हुई मौखिक बातचीत से बोफोर्स इस सौदे में करीब ५०० करोड़ रुपए कम करने पर मजबूर हो गया था।

विरोधाभासी वक्तव्य : मोरबर्ग की भारत-यात्रा के बावजूद अनेक सवाल अनुत्तरित रह गये (देखिए बाक्स)। इसका प्रमुख कारण यह है कि बोफोर्स न केवल अपनी विश्वसनीयता खो चुका है बल्कि उसके विरोधाभासी वक्तव्यों ने सारे मामले को और भी उलझा दिया है। मोरबर्ग यहां तक कह गये कि धन का भुगतान पानेवालों में कोई भारतीय नहीं है, जबकि बोफोर्स की स्वामी कंपनी नोबल इंडस्ट्रीज के मुखिया लार्स एरिक थनहोम ने २६ अगस्त को बयान दिया था कि भुगतान पानेवालों में भारतीय और विदेशी दोनों हैं। विन चड्ढा की फरारी भी मोरबर्ग के बयान को संदेहास्पद बनाती है। स्वयं बोफोर्स कंपनी का रिकार्ड इतना गंदा है कि यह संदेह और भी गहरा हो जाता है कि भारत सरकार और बोफोर्स के बीच कोई दुरभिसंधि है (देखिए बाक्स)। प्रेस-वालों को भी मोरबर्ग ने गोलमाल उत्तर दिये। बहरहाल, एक बात उन्होंने स्वीकार की कि यद्यपि प्रधानमंत्री का मामला अपवाद है, फिर भी कुछ खास लोगों को निर्दोष होने का प्रमाण पत्र बांटना ठीक नहीं है। उनके अनुसार, अमिताभ बच्चन को ऐसा प्रमाण पत्र देना बुद्धिमानी नहीं थी क्योंकि अब अनेक लोग हमसे ऐसा प्रमाण पत्र देने की पेशकश कर रहे हैं। इसने कुछ नयी मांगों और नयी अफवाहों को जन्म देना प्रारंभ कर दिया है।" वास्तव में जिस तरह से सत्ता से जुड़े लोग बोफोर्स का समर्थन पाने के लिए उससे प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये लोग शायद यह मान बैठे हैं कि यह प्रमाण पत्र उनकी राजनीतिक तरक्की में एक जरूरी दस्तावेज के रूप में काम आयेगा। राजीव गांधी के समर्थन में अकसर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करनेवाले एक पुराने कांग्रेसी नेता का तो कहना है, "विदेशी गुलामी से हमें आजाद कराने के लिए इस परिवार ने जो कुछ किया, उस पर राजीव गांधी ने एक सौदे में ही पानी फेर दिया।"

सक्रिय विपक्षी नेता : लोकदल (अजीत) के महासचिव डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का कहना है, "कुछ समय लगेगा लेकिन अपराधी पकड़ा जायेगा। मैं भी इस दिशा में कुछ कोशिशें कर रहा हूं।" जार्ज फर्नांडीस भी हाल की अपनी स्वीडन यात्रा के अनुकूल परिणामों के कारण ऐसी ही आशा रखते हैं। उन्होंने बताया, "नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट तैयार करनेवाले दो अधिकारियों—बो सेंड बर्ग और इनमार मनदेबो ने मुझसे कहा है कि उनके पास भारत के उन सुरक्षा अधिकारियों और राजनेताओं के नाम हैं, जिन्होंने दलाली प्राप्त की है। उन्हें उनके बैंक खातों का भी पता है, जहां धन जमा हुआ है।" इन सब बातों से सवाल खड़ा होता है कि भारत के अनेक विपक्षी नेताओं और बहुत से आम भारतीयों द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद स्वीडन की सरकार दलाली लेनेवालों के नाम बताने में हिचकिचा क्यों रही है। ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से करीब एक लाख लोगों ने स्वीडन सरकार से दलालों के नाम बताने की पेशकश की है। भूत-

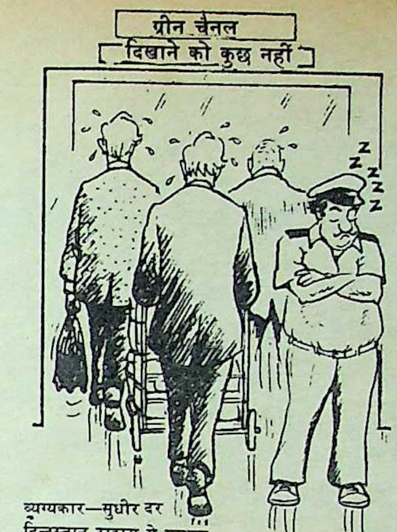

व्यग्यकार—सुधीर दर
हिन्दुस्तान टाइम्स से साभार

अनुत्तरित सवाल

यदि बोफोर्स का कहना है कि दलाली में कोई भारतीय सम्बद्ध नहीं है और दलाली का धन प्राप्त करनेवाली कंपनियां विदेशी हैं, तो फिर उसे भारतीय जनता को इन कंपनियों के नाम बताने में दिक्कत क्या है?

बोफोर्स का कहना है कि वह ग्राहकों से गोपनीयता के करार के कारण दलाली लेनेवाले लोगों के नाम उजागर नहीं कर सकती। लेकिन यहां तो मामला यह है कि खुद ग्राहक भारत सरकार ही इन नामों को जानना चाहती है, फिर यह कंपनी अपने ग्राहक को उपकृत क्यों नहीं कर रही?

क्या बोफोर्स कंपनी ने राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को पाक-साफ होने का प्रमाण देकर किसी भी तरह की 'व्यावसायिक गोपनीयता' का उल्लंघन नहीं किया है?

किस आधार पर बोफोर्स का यह कहना है, कि अनुबंध-समापन के लिए दिये गये धन का सौदा हासिल करने से कोई संबंध नहीं है?

यदि उसका कहना है कि यह भुगतान अन्य सौदों के संबंध में किया गया, तो वे सौदे कौन से हैं?

विन चड्ढा की इस सौदे में क्या भूमिका रही है? ऐसा क्यों है कि संसदीय समिति के सामने मोरबर्ग ने स्वीकार किया कि काम समेटने के लिए किये गये भुगतान में विन चड्ढा का भी हिस्सा था, लेकिन प्रेस सम्मेलन में उन्होंने इस तथ्य से इनकार कर दिया कि चड्ढा को दिल्ली में कंपनी की प्रशासनिक सेवाओं का काम देखने के एवज में धन मिला था?

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यद्यपि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है, इसके बावजूद उन्होंने स्वीडन के प्रधानमंत्री इंगवार कार्लसन को लिखा है कि वह उन भारतीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बारे में साफ-साफ पूरी बातें उजागर करें, जिन्होंने गरीब जनता का धन हड़पने के लिए अपने पद के साथ विश्वासघात किया है।

स्वीडन की सरकार ने दलालों के नाम उजागर करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली? —इस संबंध में पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि छोटे से देश स्वीडन के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत चूंकि हथियार-निर्यात है और बोफोर्स हथियार बनानेवाली स्वीडन की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए स्वीडिश सरकार बोफोर्स का पक्ष ले रही है। वैसे भी भारत से तोपों का हुआ यह सौदा बोफोर्स के लिए एकमुश्त सबसे बड़ा सौदा है। स्वीडन के विदेश व्यापार सचिव ने तब कहा था, "हमने इतना बड़ा सौदा पहले कभी नहीं देखा था।" इस सौदे से स्वयं बोफोर्स के अध्यक्ष इतने रोमांचित थे कि लंदन से प्रकाशित पत्रिका 'इकॉनामिस्ट' के अनुसार एक अप्रैल, १९८६ को (जिस दिन सौदा हुआ) बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो ने मध्य स्वीडन के कार्ल्सकोगा स्थित अपने आवास पर भारत का तिरंगा झण्डा लहराया था।

रहस्य गहरा है : वास्तव में जो दिखाई दे रहा है, रहस्य उससे भी अधिक गहरा है। जेन की डिफेंस वीकली ने १२ अप्रैल, १९८६ के अंक में लिखा था, "बोफोर्स के अनुसार यह सौदा २५० अरब क्रोनर (करीब ५००० करोड़ रुपए) तक बढ़ सकता है। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार बोफोर्स के टेक्निकल मैनेजर पर मोशबर्ग ने स्वीकार किया है कि दस वर्षों की अवधि में बोफोर्स भारत को १६०० तोपें बेचेगा और ऐसी तोपों के निर्माण के लिए भारत में एक या दो कारखाने स्थापित करेगा जिसके लिए वह सभी आवश्यक मशीनरी और साज सामान उपलब्ध करायेगा। बोफोर्स अधिकारियों का कहना है कि इस सौदे की वास्तविक कीमत बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अनेक बार यह सौदा बढ़ाया जा चुका है। वास्तव में दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि मोरबर्ग की भारत-यात्रा का मकसद मुख्यतः इस सौदे के अगले चरणों की योजना पर विचार-विमर्श करना था। एक सूत्र ने तो दावा किया है, "हथियार बनाने का यह कारखाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में स्थापित किया जायेगा।"

इस पृष्ठभूमि में यह कहना कठिन है कि स्वीडन सरकार की अपराधियों के नाम उजागर करने में दिलचस्पी है, बकौल फर्नांडीस, स्वीडन सरकार ऐसा इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि इस देश में उन्हें फिलहाल राजीव गांधी का कोई विकल्प नजर नहीं आता। फर्नांडीस का कहना है, "यही वजह है, कि मुझे राजीव गांधी से नहीं अपने आप पर गुस्सा है। मैं वास्तव में असहाय हो गया हूं।" उनकी दलील है कि फिलहाल स्वीडन सरकार यह नहीं मानती कि विपक्षियों को किसी प्रकार की मदद देना राजीव गांधी की सरकार को गिराने की गारंटी साबित होगा। उसे यह भी भरोसा नहीं है कि नयी सरकार इस सौदे को जारी रखेगी।

वास्तव में भारत के विभाजित विपक्ष ने संसदीय जांच समिति का बहिष्कार करने के अलावा बोफोर्स के मामले में कोई संयुक्त कदम उठाया ही नहीं। लेकिन यदि विपक्षी नेता संसदीय जांच समिति में रहते तो क्या वे सुनवाई के दौरान मोरबर्ग से और भी अधिक बातें उगलवाने में कामयाब हो जाते? मधु दंडवते का कहना है, "बिलकुल नहीं, यह समिति इतनी शक्तिहीन है कि कुछ भी सकारात्मक करने में असमर्थ है।" दूसरी ओर इसके मुकाबले अनेक कारणों से माना जाता है कि बोफोर्स भारत में कहीं अधिक शक्तिशाली है। विदेशों में ऐसे अनेक अज्ञात लोग हैं जो दलाली पाने के कारण बोफोर्स के मित्र हैं और वे इतने शक्तिशाली भी हैं कि वे विदेशों से स्वतंत्र भारत की नीतियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं।

—प्रकाश नंदा

आज की भागदौड़ की ज़िन्दगी में...

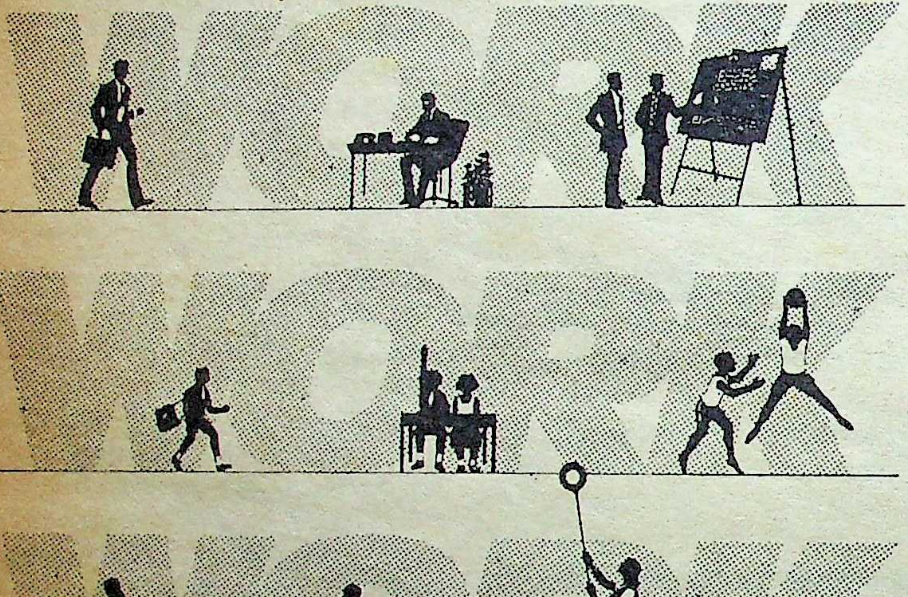

...सिंकारा आपका हर दिन खुशगवार बनाता है।

आज हर व्यक्ति अपने-आप को थका-मांदा महसूस करता है। चुस्ती और तन्दुरुस्ती के लिए केवल अच्छा आहार ही काफ़ी नहीं। आपको कुछ और भी चाहिए। 29 परीक्षणों ने सिंकारा को एक प्रभावकारी टॉनिक सिद्ध किया है। प्रतिदिन 2 चम्मच सिंकारा लेने से आपके जीवन में नई उमंग, नई स्फूर्ति जाग उठेगी।

आप को सिंकारा की आवश्यकता कब होती है:
- साधारण कमज़ोरी और दुर्बलता में
- भूख की कमी में
- कीटाणुओं के विरुद्ध शरीर में शक्ति पैदा करने के लिये
- वज़न की कमी, आदि में

cinkara
cinkara

HTA-5069 HIN

अनिवार्य तत्वों, विटामिनों और जड़ी-बूटियों का अनोखा मिश्रण

सिंकारा

विश्व-प्रसिद्ध टॉनिक, प्रत्येक ऋतु में सब के लिये

हमदर्द

' के अनु-
दिन सौदा
न आर्ड को
ने आवास
थां।
दिखाई दे
रा है। जेन
६ के अंक
सौदा २५०
पए) तक
के अनुसार
र्ग ने स्वी-
में बोफोर्स
ऐसी तोपों
कारखाने
आवश्यक
करायेगा।
इस सौदे
है, क्योंकि
है। वास्तव
है कि मोर-
: इस सौदे
मर्श करना
यार बनाने
गांधी के
जायेगा।"
ठन है कि
म उजागर
स, स्वीडन
ती क्योंकि
ी का कोई
का कहना:
धी से नहीं
असहाय हो
ल स्वीडन
को किसी
रकार को
भी भरोसा
ारी रखेगी।
विपक्ष ने
करने के
युक्त कदम
ना संसदीय
ई के दौरान
ालवाने में
कहना है,
क्तिहीन है
मर्थ है।"
गों से माना
धिक शक्ति
लोग हैं जो
त है और
ी से स्वतंत्र
की क्षमता
प्रकाश नंदा

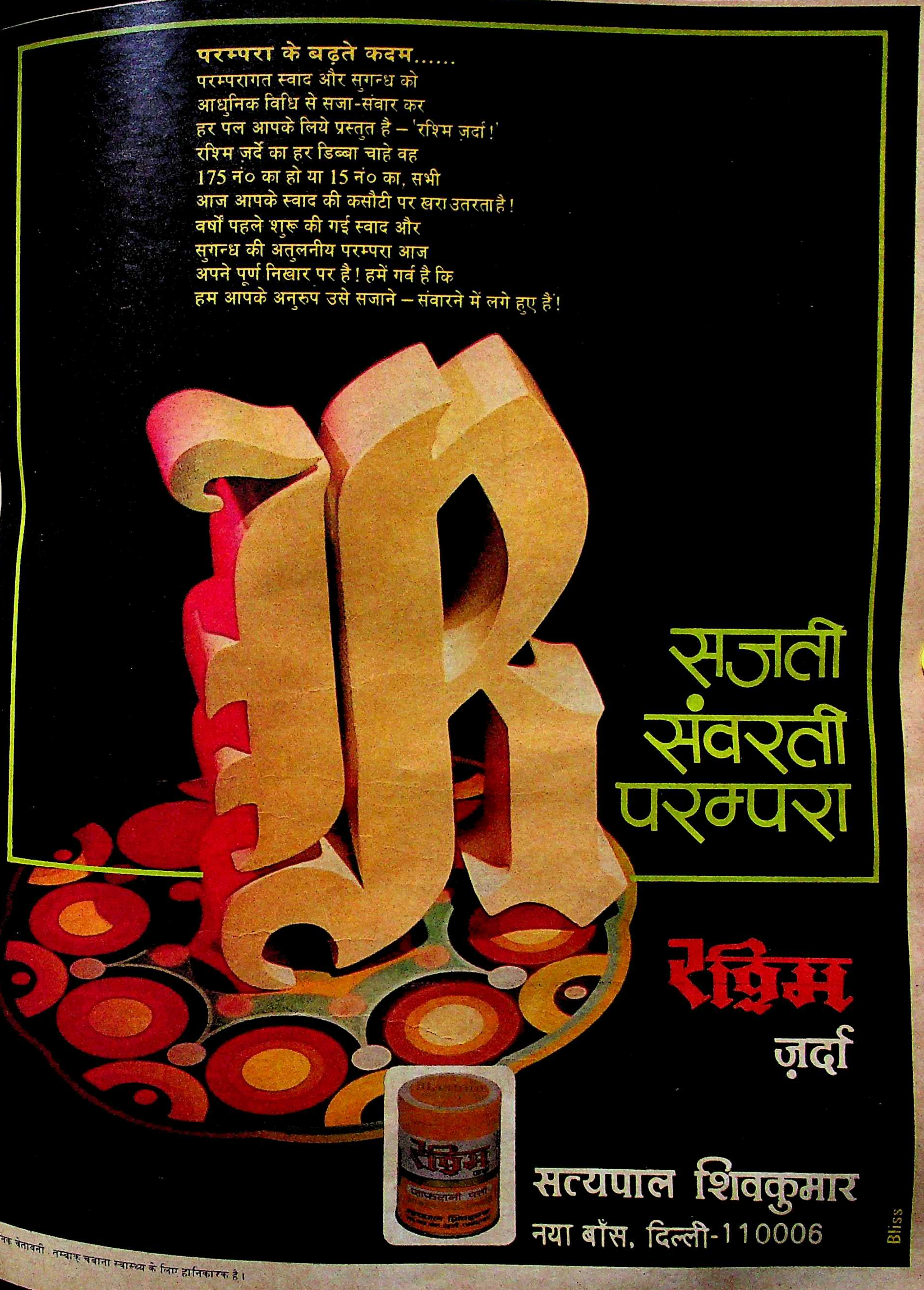

परम्परा के बढ़ते कदम......
परम्परागत स्वाद और सुगन्ध को
आधुनिक विधि से सजा-संवार कर
हर पल आपके लिये प्रस्तुत है – 'रश्मि ज़र्दा!'
रश्मि ज़र्दे का हर डिब्बा चाहे वह
175 नं० का हो या 15 नं० का, सभी
आज आपके स्वाद की कसौटी पर खरा उतरता है!
वर्षों पहले शुरू की गई स्वाद और
सुगन्ध की अतुलनीय परम्परा आज
अपने पूर्ण निखार पर है! हमें गर्व है कि
हम आपके अनुरुप उसे सजाने – संवारने में लगे हुए हैं!

सत्यपाल शिवकुमार
नया बाँस, दिल्ली-110006

वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

Bliss

मनोरमा

१५ नवम्बर' ८७

बुनाई विशेषांक

बुनाई विशेषज्ञों द्वारा तैयार नयनाभिराम नमूने पूरे परिवार के लिए

प्रमुख आकर्षण

- पुलोवर पर तैरती नाव
- चमकते सूर्य वाला पुलोवर
- नन्हे त्रिकोणवाला वनपीस पुलोवर
- नये नमूने का फ्रॉक कोट
- बेटे के लिए बुनिये बाबा सूट
- एक जैकेट किशोर-किशोरियों के लिए
- गोल गले का केबिलवाला पुलोवर
- मनमोहक हाईनेक पुलोवर
- बंद गले का पुलोवर
- कढ़ाई से सजा मनमोहक कार्डिगन
- एक सादा-सौम्य पुलोवर

आवरण कथा :

जब प्यार की धड़कन धीमी पड़ने लगे

समझा यही जाता है कि पति-पत्नी जितने ज्यादा करीब आते जाएंगे, प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, प्यार भी चाहता है कुछ दूरियां। पढ़िए एक रोचक विवेचन।

अन्य आकर्षण :

- मेरी सुहागरात : 'बिजली की वह आंख-मिचौली'
- सौंदर्य : हाथों और नाखूनों की देखभाल
- व्यंजन : खस्ता पेस्ट्री : मीठी भी नमकीन भी
- फीचर : नेत्रहीनों और विकलांगों की कार-रैली
- बच्चे और आप : क्या आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है ?
- दस्तकारी, कढ़ाई, फैशन, गृहसज्जा की लेटेस्ट डिजाइनें
- अनवर आगेवान की कहानी : 'नाथीबाई'
- सरोजनी प्रीतम की हास्य रचना : 'चाय-दर्शन'

नवम्बर प्रथम सप्ताह में प्रकाश्य

मूल्य-६.००

बिजली
ीली'
र
ल
ट्री:
भी
और
र रैली
क्या
त्तर

फैशन,
ट

ती
ई'
ी हास्य
न'
में प्रकाश्य

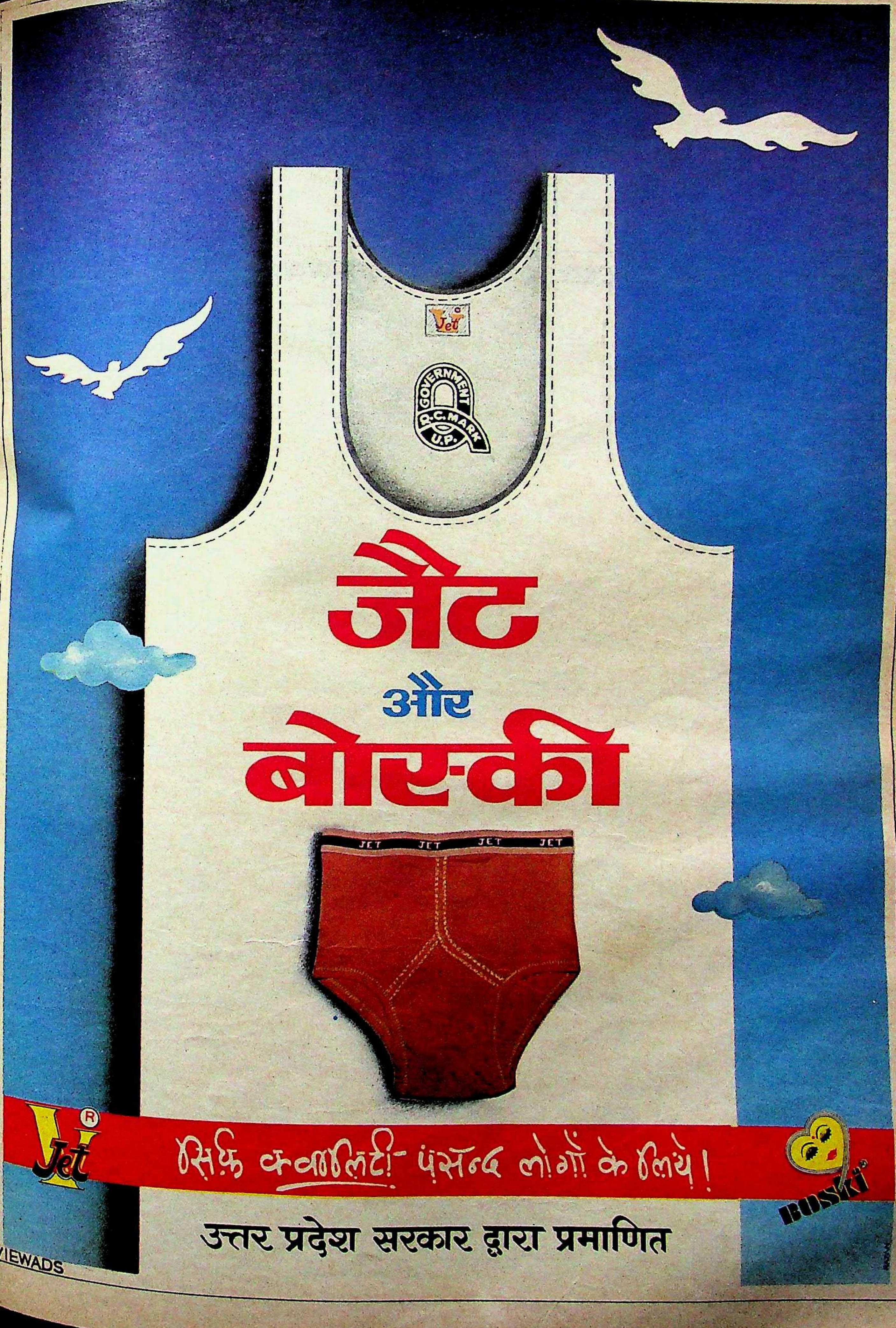
Jet
GOVERNMENT
Q.C. MARK
U.P.
जैट
और
बोस्की
JET JET JET JET
Jet ®
सिर्फ़ क्वालिटी-पसन्द लोगों के लिये!
BOSKI
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित
VIEWADS

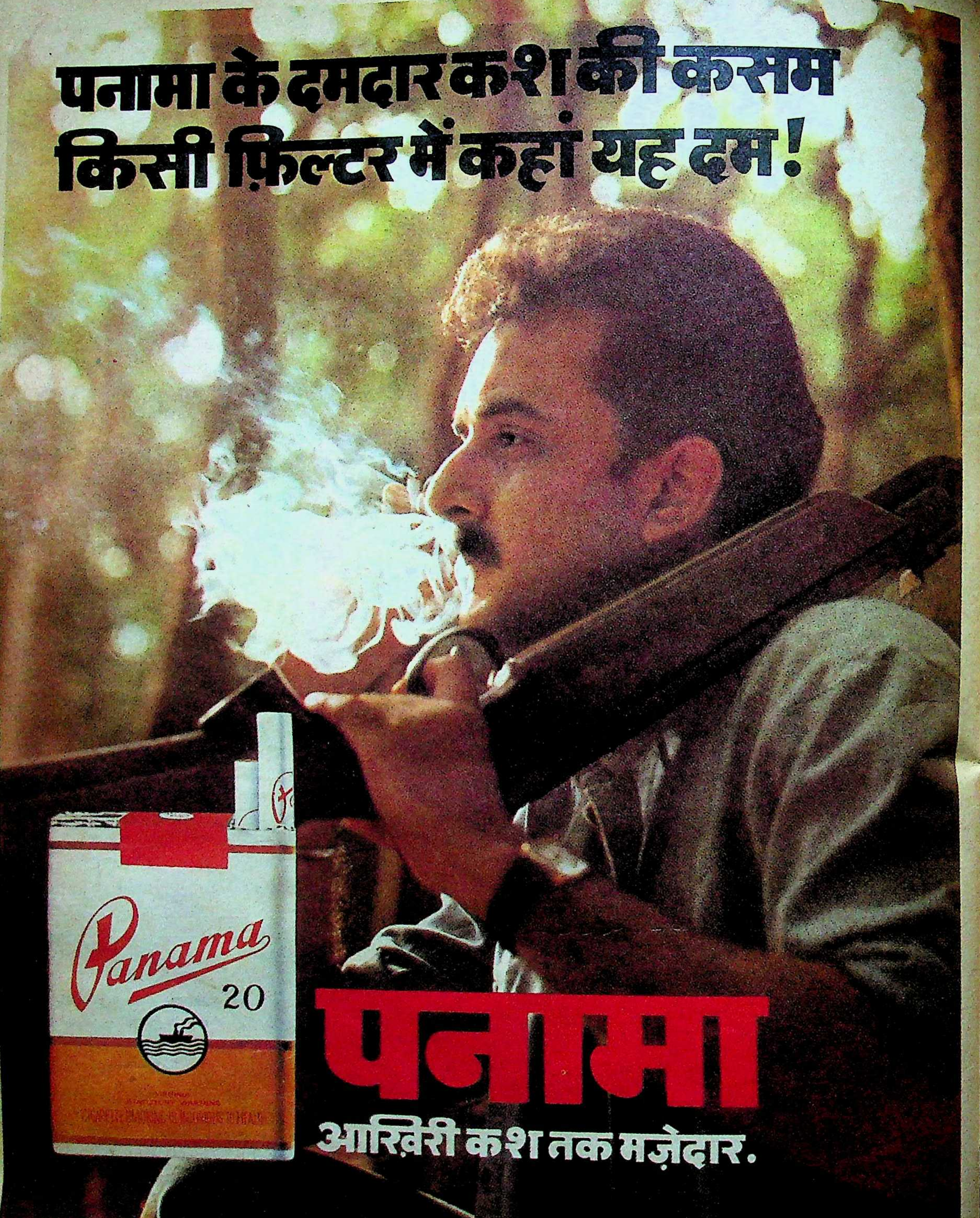
पनामा के दमदार कश की कसम
किसी फ़िल्टर में कहां यह दम!
Panama
20
पनामा
आख़िरी कश तक मज़ेदार.
Govan/PPL/1E/86/Hn

महादेवी वर्मा

इसी वर्ष ४ अप्रैल, को अज्ञेय जी नहीं रहे और ११ सितम्बर को ठीक हिन्दी-दिवस के ३ दिन पूर्व पद्मभूषण से अलंकृत और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिन्दी की एक आधार-स्तंभ महीयसी महादेवी वर्मा का प्रयाग में स्वर्गवास हो गया। अभी उनका पार्थिव शरीर अग्नि-समर्पित भी नहीं हो पाया था कि खबर आयी कि प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेंद्र पंडित 'सोज', कवि और नाटककार देवराज दिनेश और तीखे व्यंग्यकार फिक्र तौंसवी भी नहीं रहे। यह पूरा वर्ष ही हिन्दी-जगत के लिए दुर्भाग्यशाली रहा, लेकिन सितम्बर मास हिन्दी को जो क्षति पहुंचा गया उसकी पूर्ति होना असंभव है, खासकर महादेवी वर्मा के निधन से तो हिंदी-साहित्य के एक युग का पटाक्षेप ही हो गया।

२६ मार्च, १९०७ को होली के दिन फर्रुखाबाद में गोविंद प्रसाद वर्मा के घर जन्मीं महादेवीजी तकरीबन तीन वर्ष से थायरायड, सीने की जकड़न और स्पांडलाइटिस से जूझ रही थीं। विगत ७ सितम्बर से ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। लगातार चार दिनों तक वह मृत्यु से संघर्ष करती रहीं। डाक्टरों के अथक परिश्रम के बाद भी वह नहीं बचायी जा सकीं।

उनके गीतों में जो उदात्तता, मिलन-विरह, करुणा और लोकमंगल की सच्ची मार्मिक अनुभूतियां थीं, वे एक एकरस होकर आध्यात्मिक स्थिति में भी लोकरंजक हो गयी थीं। महादेवीजी ने पांच-छह वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली कविता ठाकुर जी (भगवान शंकर) के प्रति थी। वह प्रतिदिन अपनी मां को ठाकुर जी की पूजा करती देखती थीं। उसी दृश्य को उन्होंने कविता में बांध दिया:

ठंडे पानी में नहलातीं,
ठंडा चंदन इन्हें लगातीं।
इनका भोग हमें दे जातीं,
फिर भी कभी नहीं बोले हैं।
मां के ठाकुर जी भोले हैं।।

इस प्रकार, उन्होंने खड़ी बोली और साथ ही ब्रजभाषा में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। 'नीहार' उनकी पहली कविता है जिसे उन्होंने आठवें दर्जे में लिखा था। उसके बाद वह युगबोध के अनुकूल राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखने लगीं। धीरे-धीरे उनकी दृष्टि व्यापक होती गयी और वह 'छायावाद' की चतुष्टयी की अन्यतम कवयित्री हो गयीं। द्विवेदी युग में जो इतिवृत्तात्मकता और उपदेश की शुष्कता व्याप्त थी, उससे हटकर उन्होंने भावुक मन की अनुभूतियों और संवेदनाओं को संगीतात्मक लय प्रदान किया। 'नीहार' से 'रश्मि' फिर 'नीरजा' और 'सांध्यगीत' तक आते-आते उनका स्वर करुणा तथा वैराग्य से ओतप्रोत होता गया। 'दीपशिखा' तो उनकी सर्वाधिक प्रौढ़ रचना सिद्ध हुई। यामा में तो उनके कवि और कलाकार दोनों रूपों का अलौकिक दर्शन होता है।

यशस्वी कृतित्व : वह कविता को आत्मा की अभिव्यक्ति मानती रहीं और उसे पूजा-अर्चना का दर्जा देती रहीं। वह मानती थीं कि काव्य में देश, संस्कृति, उसकी धरती तथा आकाश बोलता है। इसीलिए उनकी कविताओं में प्रकृति का यथेष्ट वर्णन हुआ है। उनके काव्य में कला और संगीत का जो समन्वय हुआ है, वह विरले साहित्यकारों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार महादेवी जी की गद्यात्मक कृतियों में भी काव्यमयता और भावुकता के दर्शन होते हैं। अकसर लोगों में भ्रम है कि वह 'छायावाद' तक ही सीमित रहीं लेकिन ऐसा नहीं है। नामवर सिंह ने तो यहां तक कहा है, "महादेवी जी ने हमेशा प्रगतिशील चेतना का समर्थन किया। यथार्थवाद से सम्बन्धित उनके विचार उसके गवाह हैं। वह एक पुष्ट राजनैतिक चेतना की लेखिका थीं। आपातकाल में जब लोकतंत्र का हनन हुआ तो उन्होंने उसका खुलकर विरोध किया। वेदना को लोकव्यापी निर्वैयक्तिक करुणा में बदला। शोक को श्लोक में बदला। सांद्र स्वानुभूति और संगीतात्मकता उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है।...'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएं' में जो गद्य उन्होंने लिखा वह छायावाद से यथार्थवाद की ओर जाने का संकेत है...।"

एकाकी जीवन : महादेवी वर्मा का कोई निजी पारिवारिक जीवन नहीं रहा। ९ वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन वह पढ़ना चाहती थीं। श्वसुर स्त्री-शिक्षा के विरोधी थे। ससुराल में वह बमुश्किल २४ घंटे रहीं। रो-रोकर महादेवी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। अगले दिन उन्हें वापस मायके भेज दिया गया। फिर वह कभी ससुराल नहीं गयीं। पिता ने महादेवी को पढ़ाया। १९२७ में उन्होंने इंटर और १९२९ में उन्होंने बी०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने स्वयमेव साहस के साथ एकाकी जीवन का वरण किया और यह सिद्ध करके दिखा दिया कि महिलाएं भी उन्नति के चरम शिखर तक पहुंच सकती हैं। १९३२ में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम०ए० किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल बनीं। इस बीच उनकी साहित्य-रचना भी चलती रही और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह महात्मा गांधी, मैथिलीशरण गुप्त, पंडित नेहरू प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय कवियों के सम्पर्क में आयीं। तीस के दशक से ही वह पूरे भारत में विख्यात हो चुकी थीं। उन्हें ढेर सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शोध-संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। उनके अशोकनगर स्थित आवास को राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप दिया जायेगा।

महादेवी जी नहीं हैं, लेकिन उनका महिमामयी विराट कृतित्व हमारे सम्मुख है। (देखिए बाक्स) उनके साहित्य का प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर शोध-अनुसंधान के स्तर तक देश-विदेश में अध्ययन हो रहा है। अपनी कृतियों के माध्यम से उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। वह शरीर से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनी रहेंगी, उनसे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।

— डा० मुस्ताक अली

कृतित्व

काव्य : नीहार (१९३०), रश्मि (१९३२), नीरजा (१९३४), सांध्यगीत (१९३६), दीपशिखा (१९४२), प्रथम आयास (आतंरिक कविताओं का संग्रह, १९८४)।

संपादित काव्य संकलन : यामा (१९३६), संधिनी (१९६४), गीतपर्व (१९७०), परिक्रमा (१९७४), बंगदर्शन (१९४४), सप्तपर्णा (ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रंश के कवियों की चुनी हुई रचनाओं का कविता में अनुवाद, १९६०) हिमालय (हिमालय से संबद्ध चुनी हुई रचनाएं, १९६५)

गद्य कृतियां : अतीत के चलचित्र (सस्मरण कथा, १९४१), शृंखला की कड़ियां (नारी मुक्ति से सम्बन्धित निबंध, १९४२), स्मृति की रेखाएं (संस्मरण कथा, १९४३) पथ के साथी (संस्मरण, १९५६), क्षणदा (ललित निबंध, १९५६), साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध (अलोचना, १९६०), संकल्पिता (आलोचनात्मक लेख, १९६९), मेरा परिवार (पशुपक्षियों के संस्मरण, १९७१), संभाषण (१९७४) आदि।

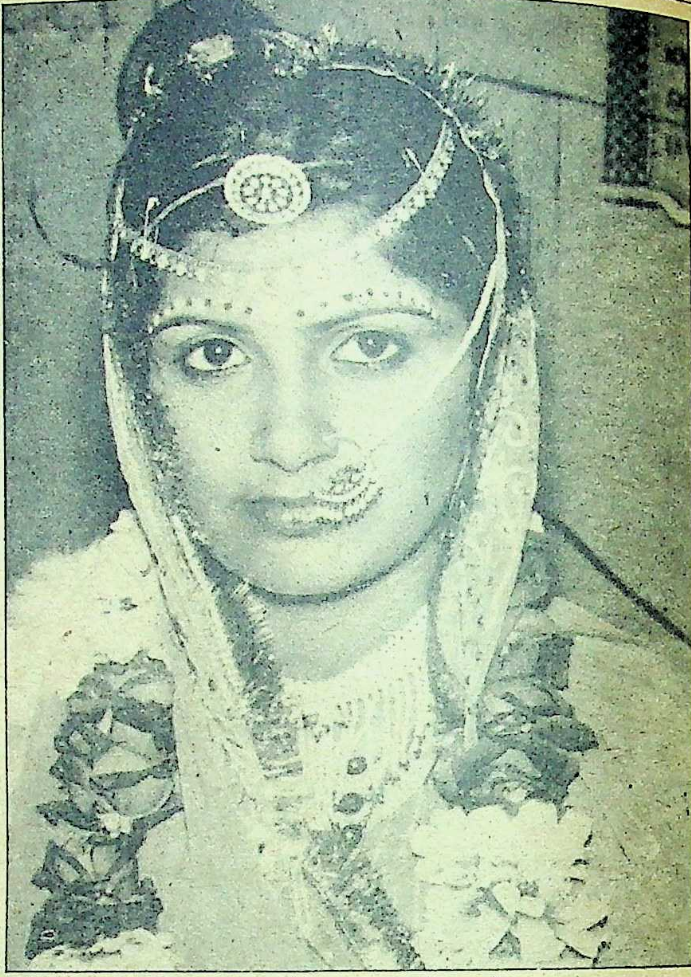

सती रूपकंवर

धर्म की ओट में स्त्री दहन

धर्म के नाम पर हत्या : १८ वर्षीय रूपकंवर विवाह के समय

४ सितंबर, १९८७ को राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में फिर एक नववधू १८ वर्षीय रूपकंवर अपने पति के शव को गोदी में लिए चिता में जिंदा जल गयी। हिंदू धर्म सती होने का कोई आदेश नहीं देता, इस जघन्य प्रथा के विरुद्ध लोगों में देशव्यापी आक्रोश है, कानूनन यह प्रथा ४ दिसंबर, १८२९ से ही प्रतिबंधित है, हर राज्य शासन को यह अधिकार है कि वह सती होने के इरादे का पता लगते ही इस काण्ड को होने से रोके और किसी कारणवश यदि यह काण्ड हो भी जाता है, तो संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ व ३०६ के तहत हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियुक्त के रूप में उस पर कानूनी कार्यवाही करे और किसी भी सूरत में इस प्रथा को महिमामंडित न होने दे। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया? जिस पुलिस ने चार मास पूर्व पाली जिले के बांगड़ी गांव में सती मैया की जय-जयकार करती २० हजार की भीड़ को तितर-बितर करके भंवरी को जिंदा जलने से बचा लिया था, जिस पुलिस ने १९८५ में देवीपुरा गांव में चिता के पास एकत्र २५ हजार लोगों को गोलियों से भून देने की धमकी देकर जसवंत कंवर को सती नहीं होने दिया था, वही पुलिस रूपकंवर को क्यों नहीं बचा सकी? इस काण्ड को धर्ममंडित श्रद्धा का प्रतीक बनने से रोकने के लिए महिला संगठनों ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर मांग की कि वह धूमधाम से होनेवाले 'चूंदड़ी महोत्सव' पर प्रतिबंध लगाये। आश्चर्यजनक रूप से राजस्थान के महाधिवक्ता ने इसे धार्मिक और पारिवारिक मामला बताते हुए इस महोत्सव का बचाव किया, तो गृहमंत्री गुलाब सिंह शेखावत ने इसे लोगों का धार्मिक मूलभूत अधिकार कहकर इस महोत्सव को रोकने में असमर्थता व्यक्त की। डेढ़ लाख लोगों की उपस्थिति में चिता स्थल पर धूमधाम से 'चूंदड़ी महोत्सव' संपन्न हुआ, जिसमें पक्ष- विपक्ष के अनेक विधायक भी शामिल थे। बहुत दबाव पड़ने पर सती-काण्ड होने के नौवें दिन अनमने भाव से मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इस काण्ड की निंदा की और एक अध्यादेश भी जारी किया, जिसमें सती बनने के लिए उकसाने या सहयोग देनेवाले व्यक्ति को फांसी तक देने की व्यवस्था है। क्या धर्मभीरु जनता के वोटों के लालच में जोशी सरकार और विपक्षी नेता 'धर्म के नाम पर हत्या' का समर्थन कर रहे हैं? पूरी-की-पूरी राजस्थान सरकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ और ३०६ के तहत अभियुक्त हो जाती है, लेकिन उसे सजा कौन देगा? क्या रूपकंवर को सती होने से बचाया जा सकता था?—ओम सैनी की रिपोर्ट:

इसी साल १७ जनवरी को १८ वर्षीय रूपकंवर का विवाह उसके पिता बालसिह राठौर ने जयपुर से ६५ किलोमीटर दूर सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के दिवराला गांव के शेखावत परिवार के युवक मालुसिंह के साथ किया था। विवाह के वक्त के चार दिन और सती होने से पहले के सात दिन, मिलाकर कुल ग्यारह दिन श्रीमती रूपकंवर ने अपने पति के साथ गुजारे थे। ग्यारह दिन के इस सान्निध्य और सात फेरों के हिन्दू संस्कारों ने श्रीमती रूपकंवर को अपने पति के प्रति इतना आसक्त बना दिया कि आंत्रशोथ (गेस्ट्रोएन्ट्राइटिस) से हुई पति की अकाल मृत्यु के साथ उसने उसकी चिता में जिंदा जलने का निर्णय कर लिया।

घटनाक्रम: २३ अगस्त को श्रीमती रूपकंवर विवाह के बाद पहली बार लम्बे अर्से के लिए हाथों में मेंहदी रचाकर अपने पीहर जयपुर से ससुराल पहुंची थी। पीहर कहे जाने वाले जयपुर अथवा राजस्थान से श्रीमती रूपकंवर का जन्म का रिश्ता नहीं था। पिता बालसिह राठौर 'रोड ट्रांसपोर्ट' का धंधा करने के लिए चालीस साल पहले नागौर जिले के कूकनवाली गांव से रांची कूच कर गये थे। वहीं रूपकंवर, उसके चार भाई और एक बहन ने जन्म लिया। रांची से रूपकंवर ने सेकेंडरी परीक्षा पास की और पहली बार राजस्थान के गुलाबी शहर में तब आयी, जब उसके पिता ने राजपूत ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम से व्यवसाय प्रारम्भ कर, उसका विवाह देवराला गांव में तय कर दिया।

आकस्मिक मृत्यु: रूपकंवर का पति माल सिंह

साक्षात्कार/मास्टर सुमेर सिंह शेखावत

श्रीमती रूपकंवर के श्वसुर.

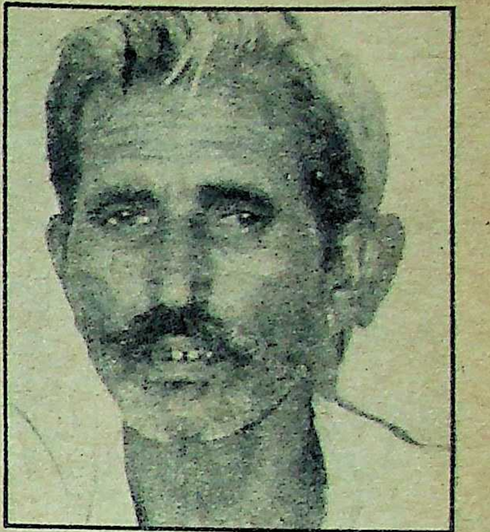

'मुझे होश नहीं था'

दिवराला श्मशान से लगभग तीन सौ मीटर दूर श्रीमती रूपकंवर का ससुरालवाला मकान है। माया संवाददाता जब वहां श्रीमती रूपकंवर के श्वसुर मास्टर सुमेर सिंह शेखावत से मिलने के लिए पहुंचा, तो वह ठाकुरों से घिरे बैठे थे। धन्यवाद के बाद बातचीत शुरू हुई। मास्टर सुमेरसिंह शेखावत काफी सोच समझकर बोल रहे थे। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश :—

माया: यह सब कैसे घटा?

शेखावत: मैं लड़की (रूपकंवर) के साथ शुरू से ही था। आई मीन टू से सीकर में इलाज करवाया उसका (मृतक मालसिह) डैड बाडी लेकर आये। रींगस (सीकर के पास एक कस्बा) के पास इसकी (मृतक) मां ज्यादा विलाप कर रही थी। फिर मेरी तबियत भी खराब हो गयी। उसके बाद मुझे भी ज्यादा पता नहीं। दूसरे दिन अजीतगढ़ डिस्पेंसरी में मैंने अपने आपको पाया। (अजीतगढ़ दिवराला से दो किलोमीटर दूर है)

माया: क्या आपके पुत्र मालसिंह की मृत्यु गेस्ट्रोएन्ट्राइटिस से ही हुई? यहां इलाज नहीं हुआ?

शेखावत: नहीं हुआ। हमारा भाई डाक्टर है, उससे कन्ट्रोल नहीं हुआ, तब सीकर ले गये।

माया: आपकी पुत्रवधू शिक्षित थी?

शेखावत: हां, रांची से सेकैन्ड्री पास की थी।

माया: श्रीमती रूपकंवर ने क्या स्वयं सती होने की इच्छा व्यक्त की थी?

शेखावत: अब मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि रींगस के बाद तो मैं बेहोश था। उसने इच्छा व्यक्त की, तभी सती हुई होगी।

मायां: कोई सती होने की चेष्टा करे, तो क्या रोकने का प्रयास नहीं करते?

शेखावत: क्यों नहीं करते? यह थोड़े ही कह देते हैं कि जाओ सती हो जाओ। पर अगली की तो भावना थीं।

माया: आप टीचर हैं?

शेखावत: जी

माया: क्या पढ़ाते हैं?

शेखावत: हिन्दी

माया: कितने साल की सर्विस हो गयी?

शेखावत: तीस साल की हो गयी।

माया: आपके परिवार में पहले भी कोई सती हुई?

शेखावत: नहीं पहली सती है।

माया: सुना है कि श्रीमती रूपकंवर के नाम से ट्रस्ट और मंदिर बनाने की योजना है?

शेखावत: अब यह तो गांव का काम है। गांव वाले कर रहे हैं और करेंगे।

माया: क्या आप सती होना ठीक मानते हैं, जबकि आपने राजा राम मोहन राय बच्चों को पढ़ाया होगा?

शेखावत: मैंने अपने दायित्व के बाहर कोई काम नहीं किया। पढ़ा-पढ़ाया तो सब कुछ है।

माया: अग्निदाह के वक्त आप थे?

शेखावत: नहीं, मुझे होश नहीं था।

माया: श्रीमती रूपकंवर के परिवारवालों की क्या प्रतिक्रिया रही?

शेखावत: पांच तारीख को आये थे, वो लोग। लड़की और दामाद का अफसोस था। चाय पी, फिर अपने बहनोई के यहां खाना खाया और जयपुर चले गये।

माया: आपके कितने बच्चे हैं?

शेखावत: मालसिह सबसे बड़ा था। दूसरे नम्बर का पुष्पेन्द्र सिंह जो ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ता है। तीसरे नम्बर की लड़की है जो पांचवी में पढ़ती है। चौथे नम्बर का भूपसिंह है।

माया: पुलिस ने केस दर्ज किया है, आपको पता है?

शेखावत: सुना है, मुझसे पूछताछ तो हुई नहीं। हां पुष्पेन्द्र सिंह से जरूर पूछताछ की थी।

माया: पुष्पेन्द्र सिंह की क्या उम्र है?

शेखावत: "पन्द्रह वर्ष"

(माया ने जब पुष्पेन्द्र सिंह से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की तो मास्टरजी ने कहा बुलवाते हैं। पर फिर पूरे दिवराला में पुष्पेन्द्र सिंह का पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने पुष्पेन्द्रसिंह को हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया और जमानत पर छोड़ दिया।)

—ओम सैनी

अंधविश्वास को बढ़ावा: चूंदड़ी महोत्सव में डेढ़ लाख लोगों की भीड़

ससुराल का माहौल भी पढ़े-लिखे लोगों का माहौल था। श्रीमती रूपकंवर के पति ने जिले के कालाडेरा महाविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में बी०एस सी० पास की थी और हाल ही में मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए होनेवाली परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण रहे थे। श्वसुर सुमेरसिंह शेखावत जिले के खेजरोली हायर सैकेन्ड्री स्कूल में हिन्दी विषय के कनिष्ठ प्राध्यापक हैं। दो छोटे देवर और एक ननद स्कूल में पढ़ रहे थे। सती प्रथा की बुराइयों और इसके कानूनी पक्ष से सभी परिचित थे।

बहरहाल, दो सितम्बर की रात मास्टर सुमेरसिंह और उसके बेटे मालसिंह ने साथ-साथ खाना खाया था। अचानक रात को मालसिंह को उल्टी और दस्त हुए। स्थानीय डाक्टर को दिखाया गया। दवा भी दी, पर हालत बिगड़ती गयी। जब हालत काबू में नहीं आयी, तो तीन सितम्बर को दोपहर सीकर के बड़े अस्पताल में मालसिंह को चिकित्सा के लिए ले जाया गया। चालीस किलोमीटर के इस सफर में श्रीमती रूपकंवर सहित सभी घरवाले मालसिंह के साथ थे। संध्या को हालत ठीक हुई, तो श्रीमती रूपकंवर व अन्य महिलाओं को बड़े बुजुर्गों ने वापस देवराला भेज दिया। पर अचानक रात को मालसिंह की तबियत ज्यादा बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गयी।

आंखों देखा हाल: श्रीमती रूपकंवर के सती होने की घटना का आंखों देखा हाल उन्हीं के परिवार के एक सदस्य ने इस प्रकार बताया, "सुबह साढ़े नौ बजे (४ सितम्बर को) सीकर से लाश लेकर आये। जवान लाश थी, इसलिए घर के अन्दर नहीं ले गये, बाहर की बैठक में ही रखा। मां और बाप सब रोने-धोने लगे। रूपकंवर ने कोई गम महसूस नहीं किया। अपने श्वसुर को किसी औरत से कहलवाया कि मुझे 'उनके' (मृतक मालसिंह) दर्शन कर लेने दो। उन्होंने मना कर दिया। बोले यह तो हमारे यहां रिवाज ही नहीं है। फिर दुबारा रूपकंवर ने ननद से कहलवाया। फिर मना कर दिया गया। इसके बाद वह बैठक के अन्दर वाले दरवाजे से जबरन शव के पास गयी। दर्शन करने के बाद उसने कहा कि मैं सती होना चाहती हूं। इस पर नृसिंहजी, शम्भूसिंह जी (रिश्तेदार) सबने मना किया। ये दोनों लोग सुमेरसिंह के भाई हैं। फिर भी उसने कहा कि मुझे तो नहाने के लिए पानी चाहिए, मैं सती होऊंगी। इस पर नृसिंहजी ने कहा कि पुलिस सती नहीं होने देगी और पिन्टू (रूपकंवर को घर में पिन्टू कहते थे) हमारी हंसी हो जायेगी। तू तो जैसे है, वैसे ही बैठी रह। इसके बाद रूपकंवर ने अपने श्वसुर के पैर छू लिए और गले पड़ गयी, "बोली पापा मुझे सती हो जाने दो।"

"रूपकंवर के श्वसुर ने कहा कि ढाई साल पहले भी पुलिस ने इस इलाके में सती नहीं होने दिया था। तू भी मजाक ही करवायेगी। रूपकंवर ने इस पर जोर देकर कहा कि नहीं मजाक नहीं करवाऊंगी।

"इसके बाद उसने स्नान करना प्रारम्भ कर दिया। अपने पति के शव के पास बैठी और गीले कपड़े से नीचे से ऊपर तक शव को पोंछा। इसके बाद उसने अपने श्वसुर से कहा कि मेरे सन्दूक में से कपड़े ला दो। इस पर सुमेरसिंह ने कहा कि मैं बहू-बेटी के सन्दूक में हाथ नहीं देता। रूपकंवर ने इस पर कहा कि आप मना कर रहे हैं, पर अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी। फिर शादी का जोड़ा निकालकर उसे कमरे में दिया गया। शादी का जोड़ा पहनने के साथ

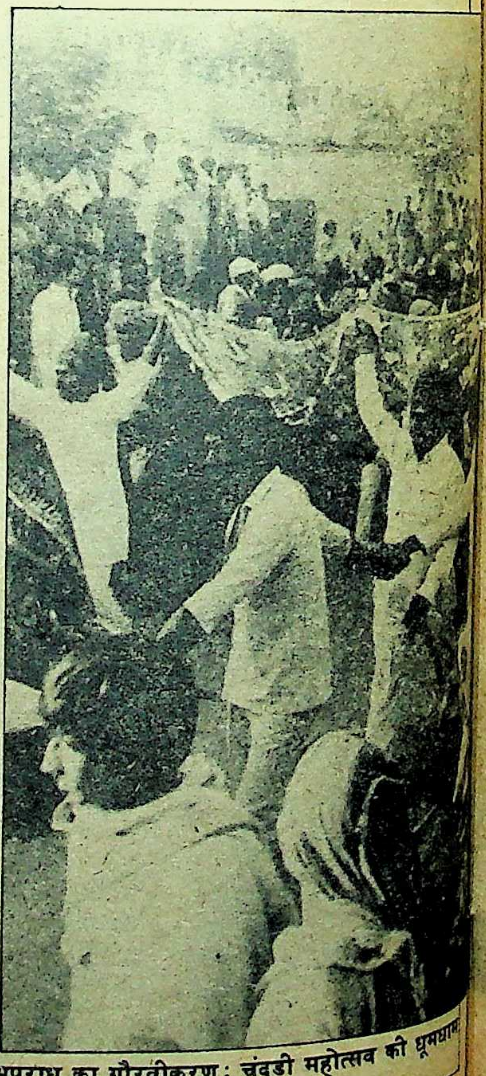

अपराध का गौरवीकरण: चूंदड़ी महोत्सव की धूमधाम

उसने सिर पर राखड़ी और हाथों में चूड़ियां पहनीं। काफी देर तक शव के पास रही, तो सुमेरसिंह ने कहा कि अब जल्दी करो, अगर सती होना है, तो। इस पर रूपकंवर ने कहा कि मैं जल्दी नहीं करूंगी, अपने समय मे ही बाहर आऊंगी। साढ़े बारह बजे वह कमरे मे बाहर आयी।

"लोगों ने पूछा कि अब किधर चलें। इस पर रूपकंवर ने कहा कि जहां अपने बड़कों (पुरखों) का श्मशान है, वही चलो। चलने से पहले उसने अपने श्वसुर से कहा कि मेरा सारा सामान मेरी ननद को दे देना और श्मशान की ओर चल पड़ी। अजीतगढ़ स्कूल में रूपकंवर का देवर पुष्पेन्द्रसिंह पढ़ता है। वह स्कूल जा चुका था। उसको वहां से अग्नि देने के लिए बुलाया गया।

"श्मशान तक रूपकंवर घूंघट मे थी। वहां पर घरवालों ने कहा कि अब आप अपना घूंघट हटा दो। लापा देने के बाद वह एक बार जलते हुए लुढ़की, लेकिन फिर खुद ही अपने को नियन्त्रित कर लिया।" अहीर जाति के बाहुल्यवाले देवराला ग्राम की आठ हजार की जनसंख्या में एक भी मर्द ऐसा नहीं था जो भावना और संस्कारों की आंधी में बहक गयी इस युवा महिला को चिता में प्रवेश करने से रोक सकता। वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष के छात्र गोपाल सिंह से जब माया ने पूछा, "जिंदा आदमी का जलना आपको अटपटा नहीं लगा?" गोपाल सिंह ने सहजता से कहा, "नहीं, गांव के लगभग चार हजार लोग इस दृश्य को देख रहे थे और जय-जयकार कर रहे थे"।

चिता के चारों ओर जंग लगी तलवारों के साथ राजपूत समाज के युवक चक्कर लगाते पहरा दे रहे थे। बताया गया कि तांत्रिकों की पकड़ से मृत-आत्माओं को बचाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है। स्कूलों और कालेजों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवक इस काम को अंजाम दे रहे थे।

श्रीमाधोपुर पंचायत समिति का एक चश्मदीद कर्मचारी उससे भिन्न विचार रखता है, उसका कहना था, "देवर पुष्पेंद्र ने जब चिता में अग्नि दी, उस वक्त रूपकंवर के एक हाथ में नारियल था और दूसरा हाथ शव पर रखा था। आग तेज होने से जब धुंवा हुआ, तो रूपकंवर ने नारियल शव पर रखकर दोनों हाथों से जबड़े भींचते हुए अपनी गर्दन थाम ली। उसकी पीठ की तरफ कोई सहारा नहीं था। आग और तेज हुई और रूपकंवर पीछे की ओर लुढ़क गयी, इसके बाद मुझसे नहीं देखा गया।"

पति के साथ सती होने का यह क्रम दिवराला गांव में सत्तर साल के दौरान चौथा था। पूर्व में श्रीमती कुंदन कंवर, झूमारानी और मिट्ठू कंवर भी अपने पतियों के साथ अग्नि में स्वाहा हो चुकी हैं।

सती होने के बाद: परम्परा के इस क्रूर कृत्य का जायजा लेने जब अगले दिन माया संवाददाता वहां पहुंचा, तो दृश्य धार्मिक-व्यावसायिकता से जुड़ गया था। दाह-स्थल को बल्लियों और रस्सों से घेरकर पवित्रता के खांचे में बांध लिया गया था। सती माता की जय-जयकार हो रही थी। जोर-जोर से कीर्तन हो रहा था। बड़े-बूढ़े, जवान, मर्द-औरतें सभी

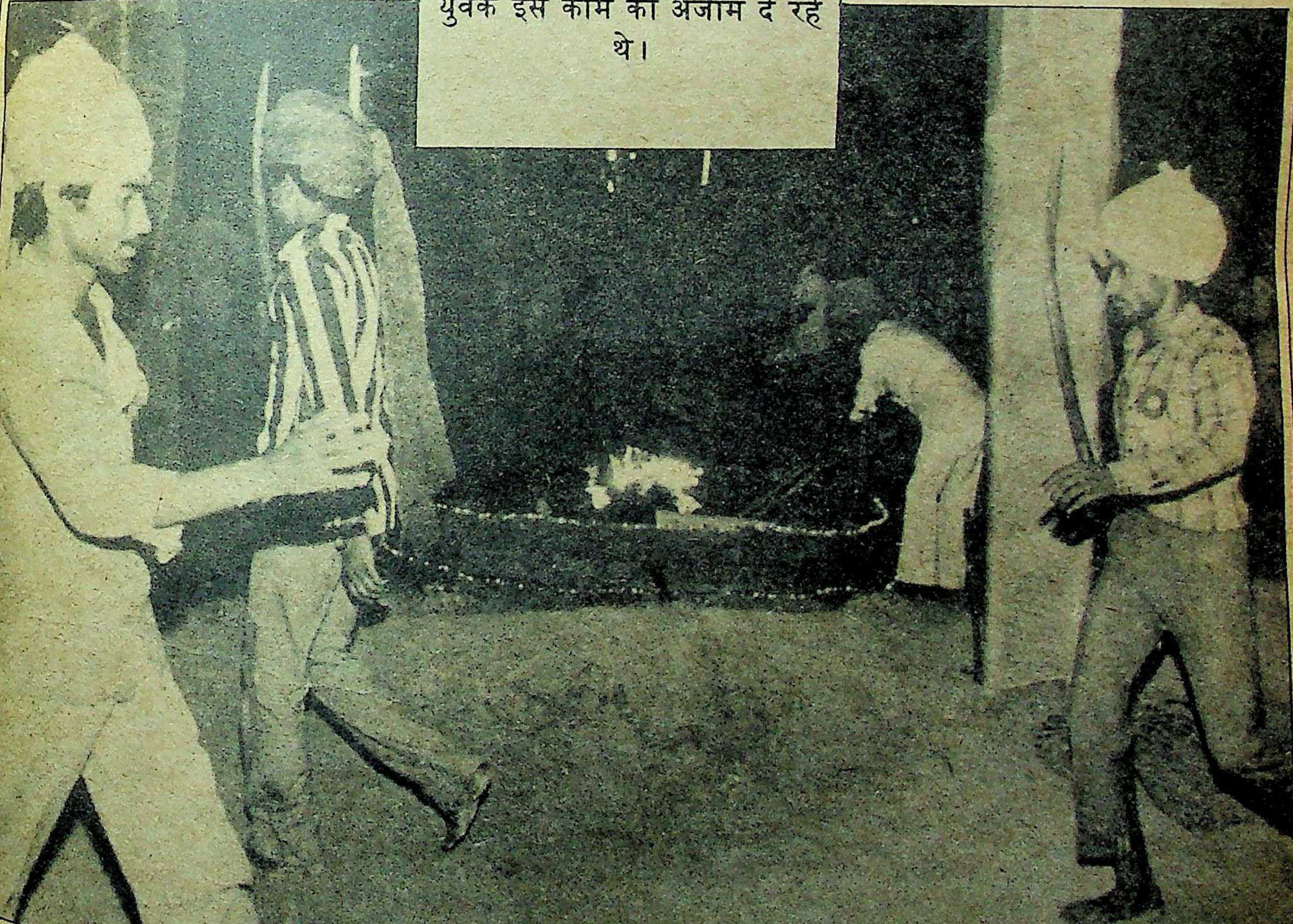

क्रूर परंपरा की रक्षा: नंगी तलवारों से सती की चिता की रक्षा करते राजपूत युवक

धार्मिक अनुष्ठान में जुटे थे। जलती हुई चिता पर नारियल चढ़ाये जा रहे थे। चाट-चाय की दुकानें खुल गयी थीं। महाजन समाज ने सूखा ग्रस्त प्रदेश में मुफ्त पानी और छाछ का इन्तजाम कर दिया था। नारियल बेचे जा रहे थे। आलम यह था कि सती माता के सामने मांग ज्यादा होने से कालाबाजारी हो रही थी। कौड़ी की चीज रुपए में बिक रही थी। गांव की औरतें सती माता के साथ लगे हाट से शृंगार का सामान खरीद रही थीं। मुर्दा आदमी के साथ जिंदा आदमी के जलने के दर्द से सब नावाकिफ थे।

चिता के चारों ओर जंग लगी तलवारों के साथ राजपूत समाज के युवक चक्कर लगाते पहरा दे रहे थे। इस पहरे की वजह यह बतायी गयी कि तांत्रिकों की पकड़ से मृत-आत्माओं को बचाने के लिए यह रक्षा व्यवस्था की गयी है। स्कूलों और कालेजों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवक इस काम को अंजाम दे रहे थे। राजा राममोहन राय के प्रयासों और कानून की दृष्टि से अपराध करार दी जानेवाली वास्तविकता से उनका कोई लेनादेना नहीं था। खोजने पर ज्ञात हुआ कि दिवराला की आठ हजार की आबादी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कम नहीं था। इस गांव में वकील, मास्टर, डाक्टर सभी उपलब्ध थे। जो तबका श्रीमती रूपकंवर के सती होने पर अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा था, उसमें गांव के राजपूत समाज के साथ-साथ महाजन और माली समाज शामिल था। अहीरों का बहुमत था, पर वे राजपूत समाज के संस्कारों से पीड़ित थे।

कानून क्या कर रहा था? : कानून की पाबंदी के बावजूद श्रीमती रूपकंवर सती कैसे हुई?

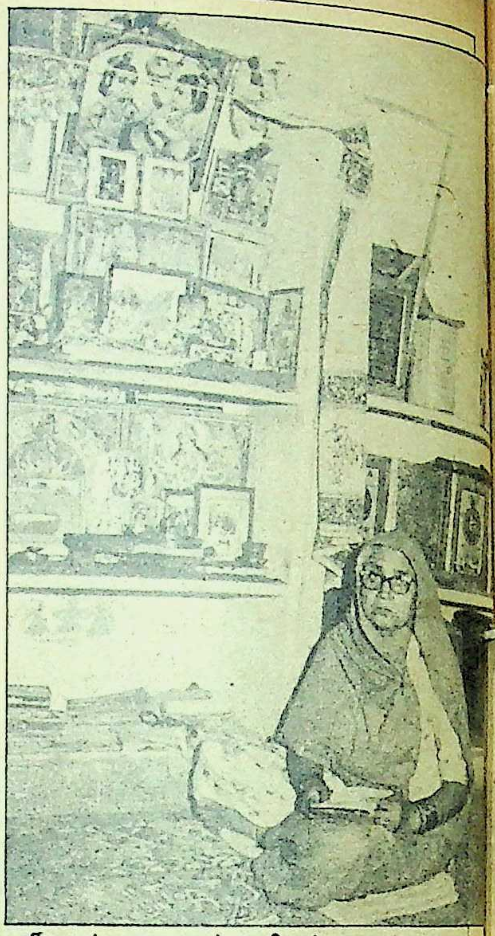

धार्मिक संस्कार : रूपकंवर की मां

इस सवाल का जवाब मिला ए०एस०आई० एस०एस० शेखावत से। तीस साल से ऊपर की वय के शेखावत सती स्थल पर उसी श्रद्धाभाव से तैनात थे, जैसा श्रद्धाभाव अन्य लोगों में नजर आ रहा था। उनका कहना था पुलिस को रूपकंवर जी के सती होने की सूचना बहुत देर से मिली। उनके अनुसार श्रीमती रूपकंवर ग्यारह बजे जल चुकी थीं, जबकि पुलिस को सूचना मिली डेढ़ बजे। इस बयान के साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया, "दो साल पहले इसी जिले के शिवपुरा गांव में एक अन्य राजपूत महिला श्रीमती जसवंत कंवर को सती होने से पुलिस ने रोका था। लाठी चार्ज और अश्रुगैस से भीड़ को तितर-बितर किया गया था। पर इस से क्या हुआ, वह आज तक अन्न ग्रहण नहीं करती।" शेखावत के चेहरे पर जातीय दर्प नजर आ रहा था।

दाह-स्थल पर यह भी प्रचारित किया गया था कि पुलिस श्रीमती रूपकंवर को सती होने से रोकना चाहती थी। दिवराला से १८ किलोमीटर दूर थोई का थाना दिवराला से लगता है। जब पुलिस वहां से चली, तो उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस सन्दर्भ में ए०एस०आई० शेखावत का कहना था कि गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पर वह थाने की गाड़ी नहीं थी और उसमें जानेवाले दो सिपाही किसी दूसरे थाने के थे। 'माया' को गांव के विभिन्न सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि श्रीमती रूपकंवर के सती होने के निर्णय के साथ ही गांव के राजपूत युवकों ने श्रीमाधोपुर से आने वाली

साक्षात्कार : बाल सिंह राठौड़

श्रीमती रूपकंवर के पिता

'तकलीफ भी हुई, गर्व भी हुआ'

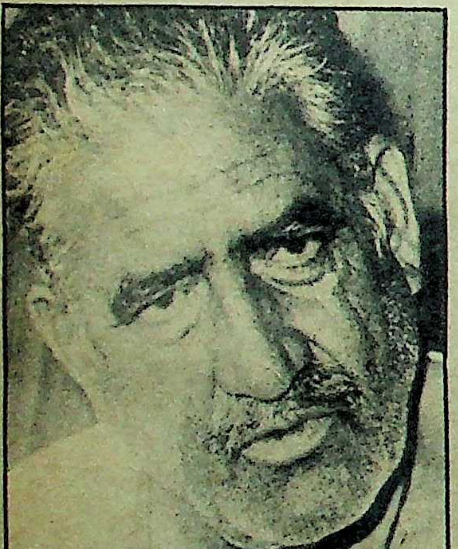

जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में 'माया' ने श्रीमती रूपकंवर के पिता बाल सिंह राठौड़ से साक्षात्कार लिया, तो वह आराम से कमरे में बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। घर के नीचे उनके चार पुत्रों में से एक गोपाल सिंह इसी इंतजार में खड़ा था कि कोई पत्रकार आये और वह अपने कुल की गौरवगाथा दर्ज कराये। बाल सिंह राठौड़ के साथ विधानसभा का आदतन चुनाव लड़ने वाले लक्ष्मीनारायण लाटरीवाले बैठे थे। पिता-पुत्र और उनके मित्र लाटरीवाले रूपकंवर के सती हो जाने से गदगद थे।

माया : आपको रूपकंवर के सती होने की खबर से कैसा लगा?

राठौड़ : आदमी तो उन्होंने (सुमेरसिंह) रात को ही भेज दिया था, पर वह कहीं सो गया। सुबह अखबारों से पता लगा, तो तकलीफ भी हुई, साथ ही गर्व भी हुआ।

माया : रूपकवर का प्रारम्भ से रुझान कैसा था?

राठौड़ : भगवान से विशेष प्रेम था। मां का असर था। हनुमान चालीसा, दुर्गाजी के पाठ करना, बस अपनी मां के साथ इसी में लगी रहती थी। हम लोग दो साल से इधर जयपुर आ गये थे, वह उधर रांची में बड़े भाई के साथ रही। वहां पूजाघर में पूजा का दायित्व वही निभाती थी।

माया : आप लोग शाकाहारी हैं या मांसाहारी?

राठौड़ : शाकाहारी। मेरे घर ऐसी कोई चीज नहीं आती। हम तो ब्राह्मणों से भी बहुत ज्यादा शुद्ध हैं। हालांकि राजपूतों में सब खाते-पीते हैं, पर हम चालीस साल से बाहर रहे। ब्राह्मण-बनियों के साथ रहे, तो वैसी ही आदतें पड़ गयीं।

माया : आप रूपकंवर का सती होना उसकी स्वेच्छा से मानते हैं?

राठौड़ : हां, वह खुद की इच्छा से ही हुई है। उस गांव में हमारे पचास-साठ रिश्तेदार हैं। उसका प्रेम ईश्वर से ऐसा था कि वही हो सकती थी, सती। मां की संगत का विशेष असर था।

इन सवालों के बाद जब 'माया' ने सती कैसे होती है, यह जानना चाहा तो पिता-पुत्र दोनों ने जिस तरह से वर्णन किया उससे लगा जैसे रूपकंवर का सती होना उनकी किसी तपस्या का परिणाम था। कहीं कोई रंज अथवा गम का नामोनिशान नहीं था।

—ओम सैनी

राजस्थान में सती परम्परा

वैसे तो राजस्थान में सतियों के कई मेले लगते हैं, पर राजस्थान के झुंझनू नगर में प्रतिवर्ष भादवा की अमावस्या को राणी सती का मेला लाजवाब है। लोक भाषा में 'दादीजी' के नाम से प्रसिद्ध राणी सती नारायणी देवी के प्रति लाखों भक्तजनों की अपार श्रृद्धा और प्रवासी राजस्थानियों की इस पर्व विशेष के लिए आस्था का मेला है। बताया जाता है कि इसमें बिड़ला परिवार हर साल शामिल होता है।

कहते हैं, राणी सती नारायणी देवी ने पति की मृत्यु पर जीवित ही अग्नि प्रवेश कर दिव्यलोक को प्रयाण किया था। उस समय हिन्दू धर्म एवं जाति पर चहुं ओर से आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे और हिन्दू जाति अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्नशील थी। उन्हीं संस्कारों में 'दादीजी' पली थीं और उन्हीं आदर्शों का अनुसरण करते हुए उन्होंने जीवन का उत्सर्ग किया था। अन्य सतियों की भांति राणी सती को भी गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वह आज से कोई साढ़े छः सौ वर्ष पूर्व सती हुई थीं।

उनके सम्बन्ध में प्रचलित है कि कभी सेठ जालानजी दास हिसार नवाब के दीवान हुआ करते थे। वह अपनी बुद्धिमता एंव चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके छोटे पुत्र का नाम तनधन दास था और नारायणी देवी का विवाह उनके साथ हुआ था।

कहा जाता है कि हिसार के नवाब के बेटे को अनजाने में मार देने के बाद तनधन दास का नवाब की सेना से भीषण युद्ध हुआ। उस समय उनकी पत्नी नारायणी देवी साथ थी। चूरू में तनधन दास वीरगति को प्राप्त हुए। इस पर नारायणी देवी विकराल रूप धारण कर रथ से कूद पड़ीं। उन्होंने पति की तलवार लेकर नवाब के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिये। उनका वह स्वरूप रणचंडी जैसा था। उन्होंने नवाब के सभी सैनिकों को मार गिराया और जब क्रोध शान्त हुआ, तो सती होने का निश्चय किया।

इस कार्य में उनकी घोड़ी के चरवाहे राणा ने उन्हें सहयोग दिया और राणी सती नारायणी देवी अपने पति के शव को लेकर चिता पर जा बैठीं। ज्यों ही ज्वाला प्रकट हुई, तो राणा ने विनीत भाव से प्रश्न किया, "मैं झुंझनू जाकर सेठजी को क्या मुंह दिखाऊंगा।" नारायणी देवी ने कहा, "तुम इस चिता की भस्म को मेरे पतिदेव की घोड़ी पर लेकर झुंझनू जाना और जहां घोड़ी रुक जाये, वही भस्म विसर्जित कर देना। फिर वह अन्तर्धान हो गयीं। कहते हैं, जहां पर वह अस्थि-भस्म डाली गयी थी, वहीं आज राणी सती नारायणी देवी का मंदिर अवस्थित है। उनके बाद भी उनके वंश में सतियां और हुई, जिनके मंडप मंदिर में बने हैं।

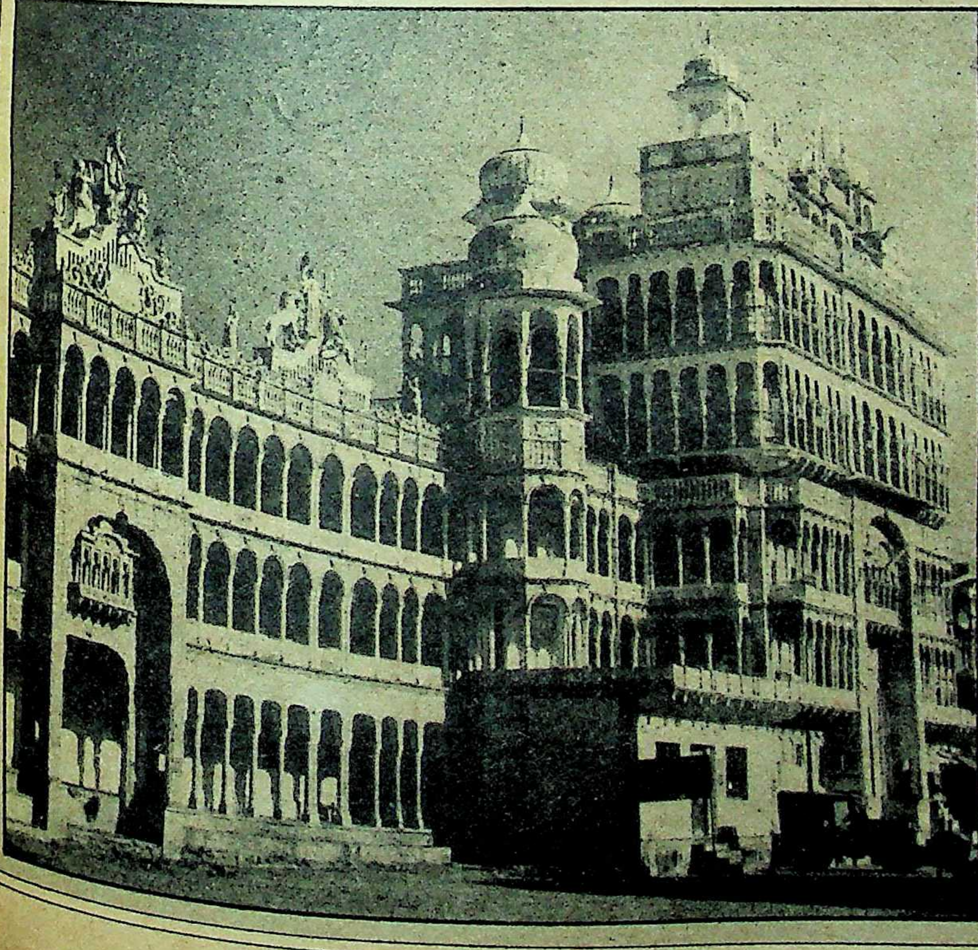

अत: ऐसा नहीं है कि केवल राजपूत राजाओं और उनके सरदारों तक ही यह प्रथा सीमित रही, अनेक उदाहरण हैं, जिनमें ब्राह्मणों, मोणवालों, नाइयों, वणिक वर्ग के लोगों ने सती प्रथा को आगे बढ़ाया। लोक-आस्था एवं सामाजिक मान्यता के कारण प्रचलित अंधविश्वासों से सती स्मारकों को मनोकामनाएं पूरी होने, मेले, धार्मिक उत्सव, प्रदर्शनी आदि आयोजनों का आवरण मिल गया। राजा-महाराजाओं की अनेकों रानियां जहां जल मरीं, वे विशेष स्थान सार्वजनिक श्रद्धा केंद्र बन गये। अनेक मंदिर, चबूतरे, स्तंभ आदि बने हुए हैं, जिनमें कुछ तो बहुत भव्य हो गये और कुछ जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं।

झुंझनू जिले के राणी सती मंदिर के अतिरिक्त अलवर जिले का नारायणी माता का मंदिर, सीकर जिले का सती सावित्री मंदिर, तथा ढांढण सती का मंदिर, जयपुर जिले का कमला सती का मंदिर, अजमेर जिले के उजायी ग्राम में तथा परेड गांव में सती के मंदिर, बीकानेर का सुसणी माता का मंदिर, वं देवकुण्ड सागर का मंदिर आदि सैकड़ों हजारों सती-स्थल लोक आस्था के धाम बने हुए हैं।

जिन स्थानों पर राजपूत महिलाएं अथवा अन्य जाति की महिलाएं सती हो जाती थीं, उन्हें महासतियां स्थल कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, आहड़, उदयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर में महासतियों के स्थल-विशेष उल्लेखनीय हैं। उदयपुर के पास महासतियां स्थल पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिंह की १० रानियां, ९ खवासने तथा ९ सहेलियां सती हुई थीं। जोधपुर के पास मंडोर में पंचकुंड नामक स्थान पर अनेक राजाओं के स्मारक बने हुए हैं, जहां उनकी रानियां सती हुई थीं।

बीकानेर में बीकाजी के उत्तराधिकारियों का बीकाजी की टेकरी के पास दाह-संस्कार हुआ और वहां कई रानियां सती हुई थीं।

बांसवाड़ा के निकट नागवाड़ा में व कुंभलगढ़ में नामादेव सती स्मारक आज भी उस युग की सती परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। जयपुर में भी अनेक स्थानों पर सती मंदिर तथा राजा-महाराजाओं की छत्रियां बनी हुई हैं, जहां उनकी रानियां सती हुई थीं।

—लक्ष्मण बोलिया

सती प्रथा और कानून

प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलित स्वरूप का लेखाजोखा उपलब्ध नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा कोई आदेश नहीं देता कि पति की मृत्यु पर उसकी पत्नी को सती हो ही जाना चाहिए। पौराणिक आख्यानों में जो देवियां सती के रूप में विख्यात हैं और पूजी जाती हैं, उसकी वजह उनकी सत्यनिष्ठा है। सती सावित्री और सती अनुसूइया अपने पतियों के शवों के साथ जिंदा नहीं जली थीं। सती-प्रथा भारत पर विदेशियों के हमलों के बाद अस्तित्व में आयी। हमलावरों द्वारा अपमानित होने से बचने के लिए भारतीय महिलाएं सामूहिक रूप से भी अग्नि—प्रवेश करती रही हैं और पति के शव के साथ चिता में जीवित जल जाने को संभवतः उन्हीं दिनों से लोक-प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हुई होगी।

मुगलकाल में खास तौर से सम्राट अकबर ने सती-प्रथा को रोकना चाहा था। लेकिन राजपूत रियासतों, ब्राह्मणों और सिखों में इस के प्रचलन और लोक-मान्यता को ध्यान में रखकर संभवतः मुगल शासकों ने इस प्रथा को अमानवीय मानते हुए भी रोकने के प्रभावी उपाय नहीं किये। उन्होंने इससे अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत करने तथा राजाओं को अपने पक्ष में लेने की राह में रुकावट महसूस की। इस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा प्रभावी रोक के अभाव में मुगल काल में इस कुप्रथा पर अंकुश नहीं लग सका।

अंग्रेजों द्वारा भारत में सत्ता सम्हालने से पहले अनेक देशी राज्यों में सती प्रथा प्रचलित थी। हर साल हजारों विधवाएं समाज और धर्म की रूढ़िगत मान्यतायों व लोक-मर्यादा की आड़ में अपने मृत पति के शव के साथ आग की भेंट चढ़ जाया करती थीं। विख्यात अंग्रेज लेखक इगलस देवार के अनुसार संपूर्ण भारत में सन १८१५ के पहले तक हर साल दो हजार स्त्रियां जलकर सती हो जाती थीं। महाराजा रणजीतसिंह के दाह-संस्कार के समय उनकी छह रानियां उनके शव के साथ सती हो गयी थीं। राजपूताने के चित्तौड़, जैसलमेर सहित कई किलों में हुए जौहर जाहिरा तौर पर सामूहिक सती की ही मिलती-जुलती घटनाएं थीं।

अंग्रेज शासकों ने सती-प्रथा के विरुद्ध कुछ कठोर क़दम उठाने का साहस किया था, परंतु सफलता नहीं मिली। बाद में राजा राम मोहन राय के सहयोग से तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक के प्रयासों को सफलता मिली। तत्कालीन बंगाल प्रेमिडेंसी में सती प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक था। सन १८०३ में लार्ड वेलजली ने हुगली नदी के मुहाने पर सागर टापू में पूजा के दौरान होनेवाले एक अबोध शिशु के बलिदान को रोक दिया था। उस वक्त हिंदू समाज ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। धर्म के ठेकेदारों ने अंग्रेजी हुकूमत की इस कार्यवाही को हिन्दू रीति-रिवाज में अनुचित दखलंदाजी माना। लार्ड वेलजली उस समय इस बुराई से बेखबर नहीं था, परन्तु कम्पनी सरकार के हितों के खिलाफ सती प्रथा को रोकने की वह हिम्मत नहीं कर सका। विख्यात अंग्रेज इतिहासकार विन्सडन स्मिथ के अनुसार अंग्रेज सरकार ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ २५ वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की। अंग्रेज शासकों के मन में सती प्रथा के प्रति विरोध का भाव जरूर था, परन्तु वे बहुसंख्यक हिन्दू समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। उसी से अंग्रेजों ने सन १८०५ तक इस प्रथा को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किये। परन्तु इस अमानवीय कृत्य को देखकर उनकी भी अन्तरात्मा आहत होने लगी। मजबूर होकर सन १८०५ में ही हिन्दू कानून के तहत सती प्रथा के बारे में विचार जानने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा सदर दीवानी अदालत की बैठक बुलायी गयी। इस बैठक में हिन्दू पंडितों ने यह व्यवस्था दी कि 'चारों वर्णों की हर स्त्री को अपने मृत पति के साथ सती होने की इजाजत है। इसमें शर्त यह होगी कि उसके कोई छोटा बच्चा नहीं हो, वह गर्भवती नहीं हो, अशुद्ध नहीं हो तथा रजस्वला होने की उम्र पार कर चुकी हो'। यदि यह व्यवस्था ईमानदारी से लागू होती, तब भी हजारों स्त्रियां सती होने से बच जातीं। परन्तु तत्कालीन धर्म तथा समाज के ठेकेदारों ने सती प्रथा जारी रखने के लिए एक रास्ता यह निकाला कि यदि किसी स्त्री के छोटा बच्चा हो और वह किसी दूसरे पुरुष को उस बच्चे की परवरिश के लिए राजी कर ले, तो उसे सती होने की इजाजत होगी।

जाहिर है कि हिंदू पंडितों ने यह रास्ता इसी उद्देश्य से निकाला कि स्त्रियां जलकर भस्म होती रहें। यह व्यवस्था कानून के विपरीत थी। यह तो विधवा को उसकी इच्छा के खिलाफ धर्म और सामाजिक व्यवस्था की दुहाई देकर जीवित जला देने का दुष्कृत्य था।

लार्ड मिन्टो ने साहस करके सती प्रथा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कानून बनाया, जिसके फलस्वरूप बंगाल में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज लेखक विन्सडन स्मिथ के अनुसार, "बहुत कम स्त्रियां अपनी इच्छा से सती होती थीं। सती होने का दृश्य अत्यन्त घृणास्पद और निकृष्टतम होता था।"

अंग्रेज शासकों ने केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में सती होने के जो आंकड़े एकत्रित कराये थे, वे बहुत ही चौंकानेवाले थे। सन १८१५ में ३७८ स्त्रियां सती हुईं। १८१६ में ४४२, १८१७ में ७०७, १८१८ में ८४६, १८१९ में ६५० तथा १८२० में ५९७ स्त्रियों ने अंपने पति की मृत देह के साथ जीतेजी अग्नि—स्नान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

सन १८२९ का वर्ष सती प्रथा के विरुद्ध हमेशा याद रहेगा। इस वर्ष लार्ड विलियम बैंटिक ने कानून बनाकर एक असरदार कार्यवाही की। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय (जो स्वयं अपने परिवार में सती की घटना से विचलित एवं मर्माहत हो घर त्यागकर चले गये थे) ने इस कार्य में बैंटिक को सहयोग दिया था।

सन १८२९ के कानून की धारा १७ के द्वारा फौजदारी अदालतों में सती प्रथा को गैर कानूनी और दण्डनीय अपराध करार दिया गया था। कानून की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया, "हिंदू धर्म में सती प्रथा आदेशात्मक कर्तव्य नहीं माना गया है। सम्पूर्ण भारत में सती प्रथा प्रचलित नहीं है। कुछ जिलों में तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। जिन क्षेत्रों में यह ज्यादा प्रचलित है, वहां यह कलंकपूर्ण अपराध नारी के साथ अमानवीय अत्याचार की सीमा लांघ जाता है। अधिसंख्य हिंदू इस हृदय-विदारक प्रथा से दुःखी हैं। वे इसे गैरकानूनी और घृणित मानते हैं।" इस कानून की जड़ें धीरे-धीरे गहरी होती गयीं। लेकिन सती-प्रथा खासकर राजस्थान में पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई। धर्म और परम्परा के नाम पर इसे कुछ इलाकों में जीवित रखा गया मगर रूपकंवर के सती होने के बाद महिला संगठनों ने इसका इतना उग्र विरोध किया कि राजस्थान सरकार को सती प्रथा के खिलाफ एक अध्यादेश जारी करना पड़ा, जिसके तहत अब ऐसे काण्डों के लिए दोषी पाये गये व्यक्ति को मृत्युदण्ड तक मिल सकता है। पता नहीं राजस्थान के निवासी इस मध्ययुगीन सती-प्रथा से कब मुक्त होंगे?

सती प्रथा
समाज का कलंक है

उग्र विरोध: सती प्रथा के खिलाफ जयपुर सचिवालय के सामने महिला संगठनों का प्रदर्शन

परिवहन बसों को गांव में ही रोक लिया। इन लोगों ने गांव के बाहर किसी भी आदमी को तब तक नहीं जाने दिया, जब तक श्रीमती रूपकंवर जलकर सती नहीं हो गयी।

श्रीमती रूपकंवर के सती होने के दिन से दिवराला में हर रोज हजारों लोग श्रद्धाभाव से पहुंच रहे थे। एक प्रबन्ध कमेटी का गठन हो चुका था जो श्रद्धालुओं द्वारा भेंट किये जा रहे पैसे का हिसाब-किताब रख रही थी। इस प्रबन्ध कमेटी की ओर से रसीदें छप गयी थीं, ग्यारह से लेकर इक्यावन रुपए तक महासती रूपकंवर के मन्दिर निर्माण के लिए दानस्वरूप लिये जां रहे थे। गांव-गांव में पोस्टर लग रहे थे कि १६ सितम्बर को सती रूपकंवर का चूंदड़ी (चूनरी) महोत्सव होगा। चूंदड़ी-महोत्सव के तहत चिता शांत की जाती है और फिर सती के भाई, बहन के नाम पर चूंदड़ी चढ़ाते हैं। यह सारा प्रचार जिस गति से हो रहा था, उससे लग रहा था जैसे सब कुछ पूर्वनियोजित है।

इधर गुलाबी शहर जयपुर के महिला संगठनों को लगा कि सती प्रथा के खिलाफ उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए। कागजी संगठन अचानक सक्रिय हुए, १४ सितम्बर को इन संगठनों ने पहली बार बड़ी संख्या में एक साथ पैदल चलकर प्रदर्शन किया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों से सूखा-पीड़ित राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन लेने की फुर्सत नहीं थी। परिणामस्वरूप इन्हें सती प्रथा के खिलाफ ज्ञापन मुख्यमंत्री के सचिव को देकर ही सन्तोष करना पड़ा।

मामला उच्च न्यायालय में: महिला संगठनों में जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती मधु सेठिया को लगा कि मात्र सरकार को ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला। स्थितियां समझते हुए श्रीमती सेठिया ने पांच अन्य महिला नेताओं के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया, "४ सितम्बर को सीकर जिले के दिवराला गांव में १८ वर्षीय रूपकंवर को जिन्दा जला दिया गया। अब उसे सती बताते हुए वहां १६ सितम्बर को बड़े पैमाने पर चूंदड़ी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए।" अगले दिन यानी १५ सितम्बर को उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के न्यायाधीश सुरेश चन्द्र अग्रवाल और पानाचन्द जैन ने दोपहर के १२ बजे याचिका की सुनवायी शुरू की। महिला संगठनों की ओर से एडवोकेट सुश्री सुनीता सत्यार्थी ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान युवक राजपूत वकीलों ने राजपूत समुदाय की ओर से पक्ष रखने की चेष्टा की। न्यायाधीशों ने जब इन वकीलों से जानना चाहा कि क्या वे सती प्रथा का समर्थन करते हैं, तो वे चुप हो गये। अदालत ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। उधर राज्य सरकार की ओर

> हर किस्म के वाहन से श्रद्धालु वहां आये और चूंदड़ी समारोह में शरीक होकर चले गये। राज्य प्रशासन ने समारोह रोकने के आदेश भर जारी किये, जबकि घटना के दस दिन बाद तक वह हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा। राजनेता को भीड़ छेड़ने से मत बिगड़ने का डर लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व ने तो सारे आयोजन को परंपरा का नाम देते हुए समर्थन में बयान भी जारी कर दिया।

सर्वोत्तमता हमारा ध्येय... सेवा हमारा धर्म

31वीं वर्षगांठ पर भारतीय जीवन बीमा निगम राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति करती है।

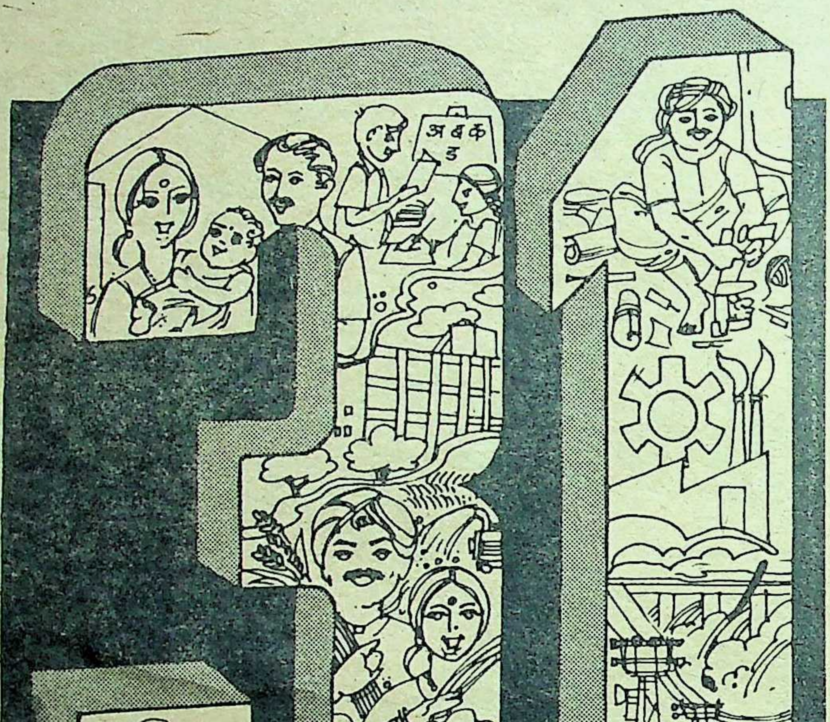

भारतीय जीवन बीमा निगम भारत के महान राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में से एक है। इसके उद्देश्य व्यक्ति एवं राष्ट्र की सेवा हेतु हैं। इसका ध्येय लाभ अर्जन न होकर सेवा भाव है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

— जवाहरलाल नेहरू
24 अगस्त 1956

Efficient/LIC 74/HN

राष्ट्र के जीवन में जीवन बीमा

भारतीय जीवन बीमा निगम

से महाधिवक्ता नाथूलाल जैन ने सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तीन बजे तक का समय चाहा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

हास्यास्पद शासन: राज्य सरकार की हास्यास्पद स्थिति इस दौरान स्पष्ट हुई। मुख्यमंत्री ने दिन के दो बजे बयान जारी कर दिवराला में हुई सती घटना की कड़े शब्दों में निन्दा की। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सती होने की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिये। जिस व्यक्ति ने मृतक की अर्थी को चिता दी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा जांच में जो-जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध सरकार कानून के अनुरूप सख्त कार्यवाही करेगी।

तीन बजे अदालत में महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की स्थिति मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट कर दी। इसके बाद न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि १६ सितम्बर को सीकर जिले के दिवराला गांव में कोई सार्वजनिक समारोह न होने दे और चार सितम्बर को वहां रूपकंवर के सती होने की घटना को महिमामंडित होने से रोके। बावजूद इसके १६ सितम्बर को दिवराला में डेढ़ लाख के करीब लोग एकत्रित हुए। चूंदड़ी समारोह पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दस बजे होनेवाला था वह आठ बजे हो गया। हर किस्म के वाहन से श्रद्धालु वहां आये और चूंदड़ी समारोह में शरीक होकर चले गये। राज्य प्रशासन ने समारोह रोकने के आदेश भर जारी किये, जबकि घटना के दस दिन बाद तक वह हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा। राजनेता को भीड़ छेड़ने से मत बिगड़ने का डर लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रान्तीय नेतृत्व ने तो सारे आयोजन को परम्परा का नाम देते हुए समर्थन में बयान भी जारी कर दिया।

उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद १५ सितम्बर की शाम दिवराला में रूपकंवर की चिता के एक ओर ३१ पंडित बैठे सवा लाख मंत्रों का जाप कर रहे थे। चिता को शांत करने के बाद चढ़ायी जानेवाली चूंदड़ी को तारों और नोटों से सजाने का काम महिलाएं कर रही थीं। उधर 'रूपकंवर महोत्सव समिति' के लोग चंदे की रसीदें काट रहे थे। इस महोत्सव के समापन तक कई लाख रुपए समिति के पास एकत्र हो गये होंगे, जबकि दुकानें खोलकर बैठे लोग हजारों का मुनाफा कमा चुके होंगे। 'रूपकवर महोत्सव समिति' के तथाकथित कार्यकर्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पत्रकारों और विशेष रूप से प्रेस फोटोग्राफरों के दुश्मन हो गये। कानून की पकड़ से बचने के लिए वह हर उस प्रयास के खिलाफ थे, जिससे चूंदड़ी समारोह के आयोजकों का चेहरा पहचाना जा सकता था। ऐसे में जो भी फोटोग्राफर १६ सितम्बर को फोटो खींचता नजर आया, उसके साथ मारपीट हुई और कैमरे तोड़ डाले गये।

आश्चर्यजनक स्थिति है कि आज भी राजस्थान का शेखावाटी इलाका उस धारणा से आजाद नहीं हो पाया है, जिसके तहत नारी की यह धारणा बनी थी कि पति के साथ सती होनेवाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है और जन्म-जन्मान्तर तक उसी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करती है। मध्यकाल में इस इलाके में विधर्मी शत्रुओं के हाथों में पड़कर कुल कलंकित न हो, इसलिए भी सती प्रथा रही है। पर आज वह डर कहां है? पारम्परिक राजपूत परिवार विशेष रूप से सामान्य राजपूत परिवार पता नहीं क्यों इतिहास के उन पृष्ठों के अंग बने रहना चाहते हैं जो आज प्रासंगिक नहीं हैं? जिन्हें राज परिवार कहा जाता है, वहां यह प्रथा बन्द हो चुकी है, लेकिन सामान्य परिवार इस प्रथा से कुलगौरव हासिल करने के लिए आज भी लालायित क्यों हैं?

छाया: गोपाल संगर

पुलिस की भूमिका

वैसे तो राजस्थान का पुलिस प्रशासन सती समस्या को आज राजस्थान में कोई समस्या नहीं मानता, पर यह सच है कि प्रदेश में सती होना आज भी जारी है। यह प्रथा उसी तरह से चल रही है, जैसे कानून का उल्लंघन कर दहेज लिया या दिया जाता है अथवा बाल-विवाह होते हैं। प्रेस और पुलिस से बचकर अथवा साठगांठ से ये काम होते हैं। बहरहाल, ऐसे भी उदाहरण है, जिसमें पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से इस कुकृत्य को रोका है अथवा जिम्मेदार लोगों को सजा दी है। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के सन १९५५ के दो ऐसे मामले हैं, जिनमें पुलिस ने जिम्मेदारी से काम किया। भीमसर गांव में १६ अगस्त, १९५५ में सरस्वती नामक महिला पुलिस के पंद्रह सिपाहियों व थानेदार के रहते सती हो गयी। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में १२ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए थानेदार हीरसिंह को निचले ओहदे पर उतार दिया। इसी गांव की गुमान कंवर के सती होने पर पुलिस ने घरवालों के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किये, पर धर्मभीरू लोगों में से एक भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप सब आजाद हो गये। सन १९८० में नागौर जिले के निमड़ी कोठारिया गांव की सुगन कंवर २६ फरवरी को सती हुई। ६२ साल की सुगन कंवर अपने ७५ साल के पति के शव के साथ चुपके से स्वाहा हो गयी। इसी तरह शाहपुरा में सरस्वती देवी सती हुई, जिसके जलते हुए चित्र 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में प्रकाशित हुए थे। पुलिस ने जयपुर जिले के देवीपुरा गांव की श्रीमती जसवंत कंवर को १२ मार्च, १९८५ को सती होने से रोका। उस समय तो डी०एस०पी० कोठपुतली ने सती-दृश्य देखने के लिए एकत्र २५ हजार की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवा में गोली चलाने के आदेश दे दिये थे। इसके पूर्व २७ जनवरी, १९८३ को इसी जिले के प्रागपुरा गांव की गोकुलबाई को पुलिस ने स्वाहा होने से बचाया।

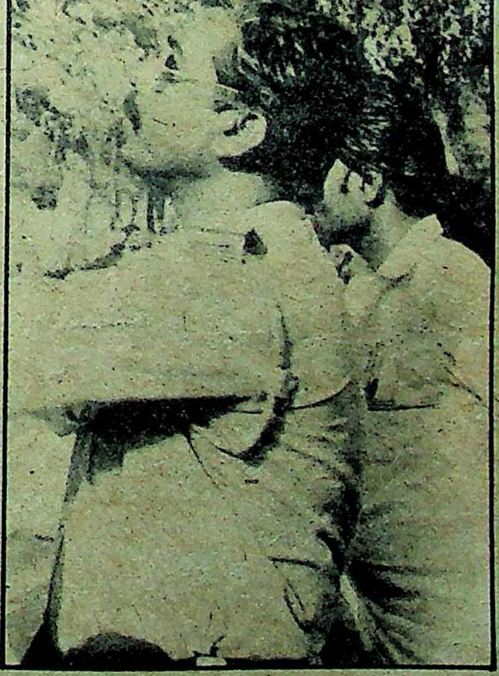

इसी वर्ष २५ अप्रैल को पुलिस ने बागदी (पाली) गांव में बीस हजार की भीड़ को भगाकर भंवरी को सती होने से बचाया था, लेकिन रूपकंवर के मामले में पुलिस की चूक पर प्रदेश प्रशासन को कोई खास अफसोस नहीं है। सीकर के डी०एम० और एस०पी० का तबादला भी राज्य शासन ने संभवतः अपना चेहरा बचाने के लिए ही किया, क्योंकि गृहमंत्री गुलाब सिंह और प्रदेश के महाधिवक्ता इस काण्ड को एक परिवार का मूलभूत धार्मिक अधिकार मानते हुए, इसे कानून की पकड़ से बाहर का मामला सिद्ध करने में लगे थे। लेकिन जब जन आक्रोश बढ़ा, तो पुलिस ने रूप कंवर के श्वसुर, देवर व नाई एवं पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऐसे सभी मामलों में हत्या व आत्महत्या के मुकदमें दर्ज करती है, जिन्हें बाद में गवाहों के अभाव में रद्द कर देना पड़ता है। सती का शाप और समाज की नाराजगी आज भी लोगों में उतना ही भय पैदा करती है, जितना मध्यकाल में किया करती थी।

—ओम सैनी

बदनाम पूर्वजों का स्मरण

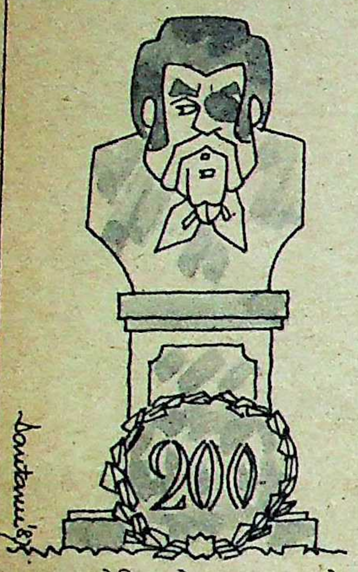

आस्ट्रेलिया के नवयुवक अपने पूर्वजों के आस्ट्रेलिया आगमन की दो सौवीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इंग्लैण्ड से २६ जनवरी, १७८८ को ७३६ लोगों का पहला जत्था आस्ट्रेलिया महाद्वीप के सिडनी कोव बंदरगाह पर उतरा था। इसकी स्मृति में आगामी २६ जनवरी से वहां दो सौवीं जयंती के समारोह शुरू हो जायेंगे। रोचक तथ्य यह है कि आस्ट्रेलिया पहुंचनेवाले ये सभी ७३६ अंग्रेज भयानक अपराधी थे, जिन्हें देश निकाले की सजा के तहत आस्ट्रेलिया भेजा गया था। इसके बाद तो इंग्लैण्ड और युरोप से ऐसे अपराधियों का आस्ट्रेलिया पहुंचने का तांता लग गया। १८४० तक ऐसे एक लाख, ६० हजार अपराधी आस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। आज आस्ट्रेलिया के अधिकांश गोरे निवासी इन्हीं अपराधी पूर्वजों की संतान हैं। बहुत ज्यादा अर्सा नहीं बीता, जब आस्ट्रलिया की पुरानी पीढ़ी को अपने अपराधी पूर्वजों से नाता जोड़ने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी बड़ी बेचैनी से जानना चाहती है कि उनके पूर्वज कौन थे? वह अपने पूर्वजों को गर्व के साथ स्मरण करना चाहती है, भले ही वे भयानक अपराधी ही क्यों न रहे हों। युवा पीढ़ी की इस बेचैनी से वहां 'पूर्वजों का पता लगाने' का नया व्यवसाय शुरू हो गया है। यह धंधा करनेवाले एक मोटी रकम लेकर लोगों को उनकी वंशावलियां तैयार करके देते हैं और उन्होंने इसके लिए बाकायदा दफ्तर भी खोल लिये हैं।

वंशावली तैयार करने में खास दिक्कत इसलिये नहीं आती क्योंकि आस्ट्रेलिया पहुंचे अपराधियों के सारे रिकार्ड उनके मूल देश में सुरक्षित हैं। आयर लैण्ड से ४० हजार अपराधी आस्ट्रेलिया पहुंचे थे। आयर लैण्ड इस अवसर पर इन ४० हजार आयरिश अपराधियों के सारे कारनामों का रिकार्ड बनाकर दो सौवीं जयंती के अवसर पर आस्ट्रेलिया को उपहार स्वरूप भेंट करेगा।

इन समारोहों का नजारा भी देखने लायक होगा। घोरतम अपराधियों की प्रोफेसर, डाक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर व मंत्री बन चुकी संतानें बड़े फख्र से अपने अपराधी-पूर्वजों के अपराधों का बखान करेंगी और संभवत: वहां वही ज्यादा आदरयोग्य और खान-दानी समझा जायेगा, जिसके पूर्वज जितने बड़े अपराधी रहे होंगे।

अटैची में मोटरकार

वह अपनी अटैची लेकर हवाई अड्डे से बाहर आये। सड़क के किनारे उन्होंने अपनी अटैची खोली। उसमें से कुछ उपकरण निकाले, कल-पुर्जों को जोड़ा और देखते-देखते १५-२० मिनट में एक छोटी सवा तीन फुट लंबी मोटरकार तैयार हो गयी। लोग आश्चर्य से देख रहे थे-वह उस कार में बैठे, कार स्टार्ट की और चलते बने।

अब वह दिम दूर नहीं जब ऐसा नजारा आम नजारा बन जायेगा। जापान जब अंगूठी में टेलीविजन बना सकता है, तो अमरीका पीछे क्यों रहे? उसने ऐसी छोटी मोटरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जिसका वजन कुल ३५ किलोग्राम है और पुर्जे खोलकर जिसे एक मध्यम आकार की अटैची में रखा जा सकता है।

हल्की नलियों के सहारे बनी यह कार सिर्फ साढ़े तीन फुट लंबी है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है। यद्यपि इसकी पैट्रोल की टंकी में सिर्फ एक तिहाई गैलन पैट्रोल आता है और यह एक गैलन में ८५ किलोमीटर तक जा सकती है फिर भी इसकी मोटर इतनी शक्तिशाली होती हैं कि एक व्यक्ति के साथ-साथ यह तीन मन वजन लेकर चल सकती है। देखना है, भारत में वे दिन कब आयेंगे जब लोग कारों में बैठने के बजाये कारों को अपनी अटैची में बिठाकर घूमा करेंगे।

जब जापानी अमरीका जाता है...

जब कोई भारतीय विदेश जाता है, तो वह वहां से इलेक्ट्रानिक्स के सामान, कैमरा, टेलीविजन, वी०सी०आर० आदि खरीद कर लाता है, लेकिन अब कोई जापानी विदेश जाता है, खासकर अमरीका, तो लौटते समय उसकी अटैची चावलों से भरी होती है। इलेक्ट्रानिक सामानों में पूरी दुनिया से आगे निकल जानेवाले जापानी विदेश में चावल देखते ही उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते।

ऐसा नहीं है कि जापान में चावल की कमी है, बल्कि असलियत यह है कि जापान में चावल उत्पादन लाबी इतनी मजबूत है कि वह चावल के भाव अनापशनाप बढ़ाती जा रही है। वहां १० किलो चावल का एक बैग ४४ डालर अर्थात करीब ६१६ रुपए में मिलता है, जबकि वही चावल अमरीका में ४ डालर अर्थात करीब ५६ रुपए में दस किलो मिलता है। टोकियो के हवाई अड्डे पर पिछले दिनों कस्टम अधिकारी यह देखकर चौंक उठे कि अमरीका से आनेवाले हर जापानी के सूटकेस चावलों से भरे होते हैं। वे अधिकारी चावल की इस तस्करी के लिए किसी को दंडित भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जापान के उस कानून के कारण बच जाते हैं, जिसके तहत हर जापानी को १०० किलोग्राम तक रसोई का सामान बिना किसी रोक-टोक के लाने की इजाजत है।

जापानी मूल के एक अमरीकी ने तो लासऐंजिलस में चावलों की एक दुकान इन जापानी खरीदारों को ध्यान में ही रखकर खोल ली है। वह एक, पांच और दस किलोग्राम के खास पैकेटों में चावल बेचता है। इन दिनों उसका धंधा जोरों पर चल रहा है।

संयोजन : विनोद मिश्र

र० आदि
ा अब कोई
, खासकर
ाय उसकी
होती है।
ूरी दुनिया
जापानी
ही उसे
नहीं पाते।
जापान में
असलियत
ल उत्पादन
वह चावल
ती जा रही
ल का एक
रीब ६१६
वही चावल
ति करीब
मिलता है।
पर पिछले
वह देखकर
आनेवाले
वलों से भरे
ल की इस
दंडित भी
ब जापान
च जाते हैं,
को १००
ा सामान
लाने की

अमरीकी
ावलों की
ीदारों को
ती है। वह
लोग्राम के
ना है। इन
र चल रहा

नोद मिश्र

'शाही लिबास

एकमात्र सर्व विजेता!

प्योर वूल एवं पोलियस्टर वूल
सूटिंग्स, ट्वीडस, ब्लेज़र्स, निटिंग वूल
कम्बल, शालें व लोइयां

मैड्रिड, स्पेन में 'क्वालिटी टेक्सटाइल एण्ड
रेडी टू वीयर' वर्ष 1987 के लिए अंतर्राष्ट्रीय
स्वर्ण पदक के लिए चुना गया

Lalimli
Dhariwal

111 वर्षों से

एक मनभावन संकलन

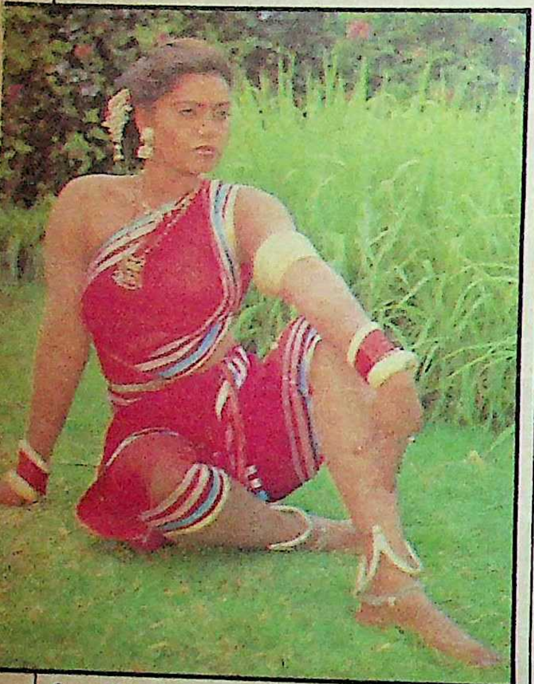

सिल्क स्मिथा छाया : धर्म मूलचंदानी

सिल्क स्मिथा की सिल्की काट

फिल्म 'सदमा' में अपने ग्लैमरस एवं सेक्सी दृश्यों से हेलेन और बिंदु जैसी वर्षों से जमी जमायी खलनायिकाओं से लेकर कल्पना अय्यर तक का पत्ता साफ कर वापस मद्रास लौट जानेवाली दक्षिण की सिल्क स्मिथा ने अब बंबइया फिल्मों की ग्लैमरस अभिनेत्रियों को भी मात देने का निश्चय किया है। सेक्स प्रधान फिल्मों का बाजार इधर पुनः गरम हो जाने के कारण सिल्क स्मिथा ने बंबइया फिल्म निर्माताओं को सुझाव दिया है कि वे यदि मलयालम की सेक्स प्रधान फिल्मों और एन० एफ० डी० सी० द्वारा आयातित 'गरम' फिल्मों के बजाय ऐसी फिल्में सीधे हिंदी में बनायें तो वह उन्हें पूरा सहयोग देगी। सिल्क स्मिथा, श्रीदेवी को अपनी 'नंबर वन' प्रतिस्पर्धी मानती है। उसका कहना है, "हम दोनों की (एक तरह) पहली हिंदी फिल्म 'सदमा' थी। 'सदमा' के बाद जितनी मांग मेरी बढ़ी थी, श्रीदेवी की नहीं। अगर मैं वापस मद्रास नहीं चली जाती, तो श्रीदेवी की जगह मैं होती। ग्लैमर, सेक्स और अंग-प्रदर्शन में श्रीदेवी भला मुझे कब पछाड़ सकती थी—जो फिगर मेरे पास है, वह भला श्रीदेवी के पास कहां?"

स्मिथा अमिताभ के साथ हीरोइन बनने के बजाय जीतेंद्र की हीरोइन बनना चाहती है, "अमिताभ में क्या है भला? अरे जीतू! हाऊ स्वीट! बड़ा लकी स्टार है, उसके साथ जो भी साउथ की हीरोइन (जयाप्रदा, श्रीदेवी, भानुप्रिया आदि-आदि) आयीं, सुपर हिट हो गयीं।" अब यह बात और है कि 'गेट आउट' के चौखट पर खड़े जीतू जो दिनभर नारियल पानी पीकर, सुबह बैडमिंटन और शाम को फुटबाल खेलकर सोलह वर्ष का दीखने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक पता नहीं सिल्क स्मिथा की यह बात पहुंची या नहीं?

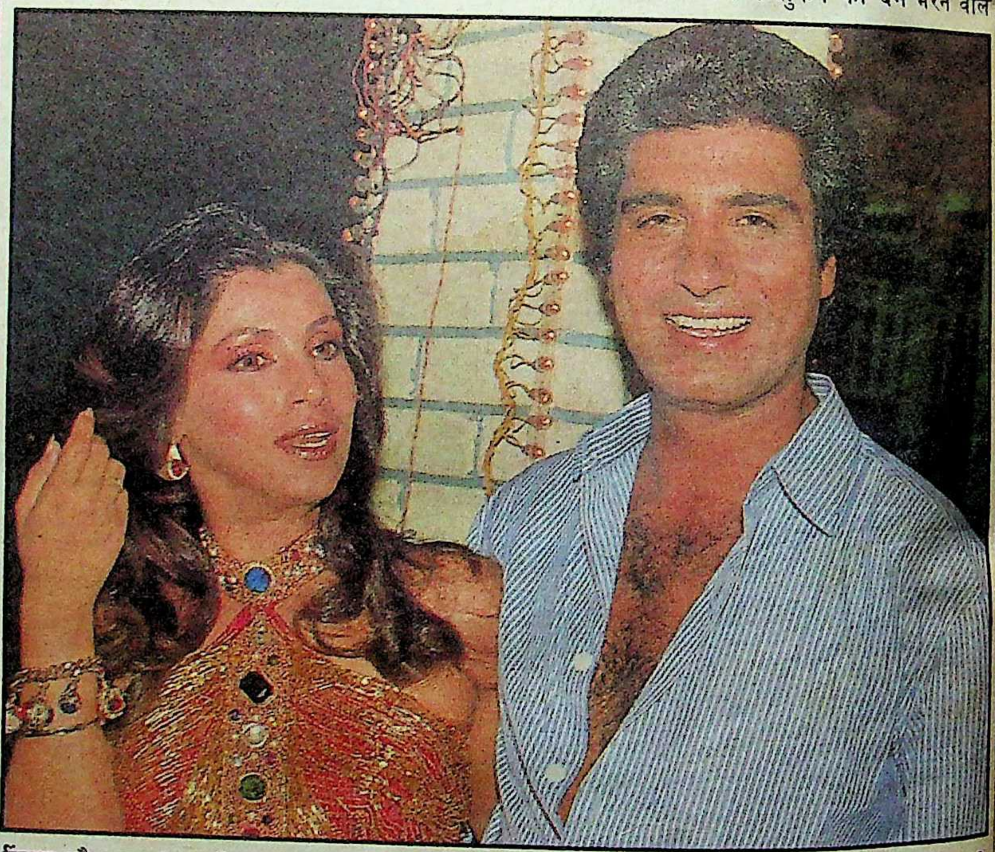

डिंपल और राजबब्बर फिल्म 'इंसानियत के दुश्मन' में छाया : धर्म मूलचंदानी

डिंपल की दोस्ती, डिंपल की दुश्मनी

लगता है, डिंपल ने काका (राजेश खन्ना) के दुश्मनों से दोस्ती और दोस्तों से दुश्मनी का जैसे मुहिम चला रखा है। फिल्म 'राजपूत' के निर्माण के समय से ही काका के दुश्मन बन गये धर्मेंद्र के बेटे सन्नी के साथ रोमांस का चक्कर चला कर डिंपल ने पहले काका को खूब जलाया और फिर गरम 'धरम' के साथ फिल्म 'बटवारा' में नायिका की भूमिका करके 'काका' को एक और मात दे दी। सन्नी के साथ दोस्ती की बात काका इसलिए हजम कर गये थे कि तब उसके पास डिंपल को पटखनी देने के लिए टीना थी, लेकिन धरम के साथ फिल्म 'बटवारा' की शूटिंग करने के कारण काका धरम से इतना खफा हुए कि उसने उस कार्यक्रम में जाने से ऐन मौके पर मना कर दिया जिसमें धरम (धर्मेंद्र) भी जाने वाले थे।

लेकिन दोस्ती-दुश्मनी के चक्कर में मारे गये राज बब्बर। काका से दोस्ती (फिल्मी एवं राजनीतिक दोनों) का मजबूती से हाथ पकड़नेवाले राज बब्बर पर डिंपल इस कदर नाराज हुई कि उसने उन फिल्मों से राज बब्बर को निकलवाना शुरू कर दिया, जिसमें वह उसके साथ हीरोइन की भूमिका कर रही थी। रेखा-शबाना जैसी बिगड़ैल हीरोइनों के सामने सिद्धांत के नाम पर न झुकने का दम भरने वाले मुजफ्फर अली तक ने डिंपल की जिद्द पर राज बब्बर को फिल्म 'हब्बा खातून' से हटा कर 'काका के नंबर वन दुश्मन' विनोद खन्ना को ले लिया और राज बब्बर के साथ शूट की हुई तमाम रीलें 'स्क्रैप' कर दीं। 'एक और नंबर वन दुश्मन' अमिताभ के साथ डिंपल चार फिल्में कर ही रही है। डिंपल को 'दो बेटियों की बूढ़ी मां' का रुतबा देनेवाला काका नयी शह की ताक में है।

मिट्ठू का शनि-योग

तीन-तीन नायकोंवाली फिल्मों में कमर मटका कर नाचने और हीरोइन से रोमांस करने की भूमिकाएं गोविंदा, सुमीत सहगल, चंकी पाण्डे ने क्या झटक लीं कि मिथुन चक्रवर्ती के लिए कैरियर के लाले पड़ गये। बहुसितारीय फिल्मों के नायक की दूसरी भूमिकाएं फिल्म निर्माताओं ने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जीतेंद्र, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर के लिए 'रिजर्व' कर दीं। जिस मिथुन को फिल्म वितरक आंख मूंद कर मनमांगी कीमत पर खरीदने के लिए उतावले रहते थें, उसी की फिल्म श्रीदेवी जैसी हीरोइन होने के बावजूद हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हैं।

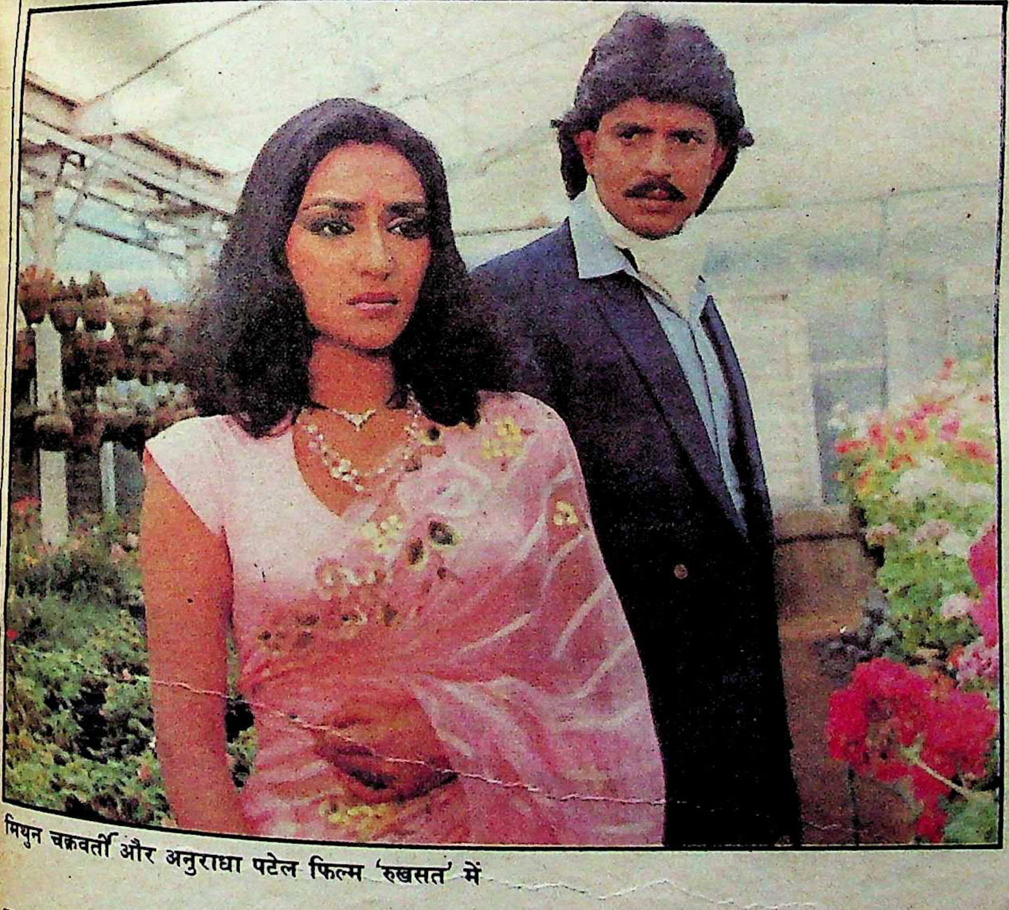

मिथुन चक्रवर्ती और अनुराधा पटेल फिल्म 'रुखसत' में

पिछले वर्ष मिथुन की जो 'प्राइस' ५ लाख रुपए से रातोंरात बढ़कर २० से २५ लाख रुपए पहुंच गयी थी, अचानक घटकर ४ लाख रुपए हो गयी। बहुत से निर्माताओं ने उसकी जगह संजय दत्त को ले लिया है और फिल्म 'खुदगर्ज' के हिट होते ही उसकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा को पेश-ए-खिदमत करने लगे हैं। कइयों ने लगे लगाये सेट पर, मिथुन की फिल्म को डिब्बे में बंद कर, नयी फिल्मों कर शूटिंग शुरू कर दी है।

लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मिथुन को तब लगा जब पिछले वर्ष उसकी खुशामद कर उसके साथ हीरोइन की भूमिकाएं करने के लिए बेहद लालायित डिंपल, किमी काटकर, मंदाकिनी, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लों तक ने अब उससे किनारा कस लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश है—अनुराधा पटेल, क्योंकि उसे अब अपना कैरियर उजला नजर आने लगा है। उसका कहना है, "मिथुन के सितारे गर्दिश में हैं, अगले वर्ष वह फिर स्टार बन जायेगा, इसलिए अधिकतम फिल्में 'मैं' उसके साथ साइन कर रही हूं। मिठ्ठी की एक भी फिल्म हिट हुई कि निर्माताओं की भीड़ उसके इर्द-गिर्द जुटने लगेगी और हमारी जोडी चल निकलेगी।" तब क्या करेगी बेचारी श्रीदेवी।

शत्रुघ्न सिन्हा छाया : धर्म मूलचंदानी

बिहारी बाबू का जलवा

"मैं गया ही कहां था जो मेरी वापसी हुई, वापसी तो उनकी (वह राजेश खन्ना या विनोद खन्ना का नाम नहीं लेते) होती है, जिन्हें इंडस्ट्रीवाले धक्के मार कर निकाल देते हैं या शराफत का चोंगा पहन कर वे खुद किनारा कस लेते हैं कि कहीं इंडस्ट्रीवाले उन्हें भी..." कहनेवाले बड़बोले शत्रुघ्न सिन्हा इस बार श्रीदेवी की तरह 'लाइम लाइट' में हैं। फिल्म 'खुदगर्ज' के बिहरिया ने शत्रुघ्न सिन्हा को असली बिहारी बाबू के रूप में जमा दिया है। एक साल पहले कटाक्ष लहजे में 'अरे वह बिहारी बाबू! कह कर शत्रुघ्न सिन्हा की खिल्ली उड़ानेवाले लोग अब बड़े फख्र से 'अरे अपने बिहारी बाबू' कहने लगे हैं। फिल्म 'खुदगर्ज' की सफलता के साथ-ही-साथ 'भाई हो तो ऐसा' के जमाने से जीतेंद्र के साथ चले आ रहे मनमुटाव को भी शत्रु ने नेताई लहजे में यह कह कर "अरे भई, जहां दो बर्तन रहते हैं, खटकते ही रहते हैं। जब तक बर्तन आपस में बजे नहीं मजा नहीं आता" खतम कर दिया है। प्राण और देव आनंद से भी शत्रु ने संबंध सुधार लिये हैं। और-तो-और 'राजा साहब' (विश्वनाथ प्रताप सिंह) को भी लेकर बाजवक्त शगूफे छेड़नेवाले बिहारी बाबू ने अब उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बिहारी बाबू इस सबसे भी बड़ी विजय जो अपनी मानते हैं—सुभाष घई द्वारा शत्रु के घर आकर फिल्म 'देवा' में अमिताभ बच्चन वाली भूमिका कर लेने की याचना करना। "अरे घई तो अपना बच्चा है, पूना इंस्टीट्यूट से साथ लगा था, हीरो नहीं बन सका, तो लेखक बन गया, भाइयों ने उसे वहां भी फेल कर दिया तो 'डिरेक्टर' बन गया। आखिर जाता कहां आना तो उसे अपने ही पास था न।" यों सुभाष घई पहले ही खम्भ ठोंक कर और अब फिर ऐलान कर चुके हैं कि इस विलेन को हमने ही फिल्म 'विश्वनाथ' से हीरो बना दिया और फिल्म 'देवा' से सुपर स्टार बना देंगे। बहरहाल, शत्रु के जलवे से घई भी चकित हैं। ■

ताज़गी का
एक पल...
...एक पल
में ताज़गी
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
FUSION/RAJ/4

रजनीगन्धा
पान मसाला

तुलसी ज़र्दा घराने की अनुपम भेंट

बाडी लाइन

छोटे परदे पर खूनी क्रिकेट

४५ वर्ष पहले आस्ट्रेलिया में हुई रोमांचक खूनी टेस्ट श्रृंखला और उसके नायक महान क्रिकेट खिलाड़ी ब्रैडमैन की जिंदगी पर जब कुछ समय पहले ४० लाख डालर की लागत से बनी टी०वी० फिल्म 'बाडी लाइन' बनी तो समूचे विश्व में हंगामा-सा बरपा हो गया। इस फिल्म को अगस्त के तीसरे सप्ताह में दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया गया, तो हर व्यक्ति सारे कार्यक्रम रद्द कर इसे देखने के लिए अपने टी०वी० सेटों के सामने आ जुटा। १३ एपीसोडों में विभाजित तथा हर रविवार को प्रदर्शित इस सीरियल में नवाब मंसूर अली पटौदी के पिता तथा उस जमाने के मशहूर खिलाड़ी सीनियर पटौदी उर्फ इफ्तिखार अली खान की भूमिका के लिए बंबई के रंगमंच अभिनेता अशोक बांठिया को चुना गया। प्रस्तुत हैं, अशोक बांठिया से 'माया' की हुई बातचीत व मुलाकातों के आधार पर इस सीरियल से संबंधित जानकारियां:

ह्यूगो वीविंग और अशोक बांठिया क्रमशः जार्डिन एवं नवाब पटौदी की भूमिका में

अशोक बांठिया

रविशास्त्री के टी०वी० सीरियल 'दैट्स क्रिकेट' के जाते ही दूरदर्शन ने 'सुनील गावस्कर प्रजेन्ट्स' का तोहफा क्रिकेट प्रेमियों को दिया। लेकिन १३ पारी खेलने के बाद जब गावस्कर विदा होने को हुए तो खेल-दर्शक इससे पहले कि 'रिक्तता' महसूस करें 'बाडी लाइन' टी०वी० सीरियल का प्रसारण शुरू हो गया।

४५ वर्ष पूर्व आस्ट्रेलिया में हुई सबसे चर्चित और विवादास्पद क्रिकेट श्रृंखला, जिसे खूनी श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, के छींटे आज भी तत्कालीन लोगों के दिमाग पर तरोताजा हैं। 'बाडी लाइन' में उसी श्रृंखला को टी०वी० के परदे पर अवतरित किया गया है।

आस्ट्रेलिया के दो फिल्म निर्माताओं टैरी हाईस तथा जार्ज मिलर ने इस श्रृंखला की लोकप्रियता को टेलीविजन पर भुनाने के लिए ४० लाख डालर के खर्च से इसे तैयार किया। जब योजना को स्वरूप दिया जा रहा था तभी इस श्रृंखला के तीन प्रमुख पात्रों डगलस जार्डिन, हेराल्ड लाखुड तथा डान ब्रैडमैन की भूमिका को जीवंतता प्रदान करनेवाले कलाकारों की भी खोज जारी थी। अंग्रेज दिखनेवाले कलाकारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन निर्माताओं के समक्ष दिक्कत थी इंग्लैंड टीम के एकं प्रमुख स्तंभ—इफ्तिखार अली खां (सीनियर पटौदी) की।

अंततः ह्यूगो वीविंग, गैरी स्वीट तथा जिम होल्ट का क्रमशः जार्डिन, ब्रैडमैन और लारवुड की भूमिका के लिए चयन हो गया, किंतु पटौदी के चेहरे की शुरू हुई तलाश सिडनी में 'निडा' (आस्ट्रेलियाई रंगमंच संघ) में पूरी हुई। 'निडा' के प्रिंसिपल जान क्लार्क ने इस संबंध में अशोक की खूब मदद की और 'बाडी लाइन' के निर्देशकों में से एक जार्ज ओगिल्वी (अन्य दो हैं—कार्ल शूड्स तथा लीज पेरनीस) से मुलाकात करवायी।

अशोक इस संबंध में एक बड़ी रोचक घटना बताते हैं, "'निडा' में मैं अकेला भारतीय था इसलिए भारत की योग तथा अध्यात्म की बात को लेकर वहां के छात्र हमेशा मेरे ही पास आते। इसीलिए बाद में मैं उन लोगों की 'बाडी एंड माइंड' की क्लास लेने लगा था। जब पता चला कि 'बाडी लाइन' के लिए मुझे बुलाया गया है, तो पूरा विश्वास था कि योग के बारे में ही कुछ होगा, लेकिन वहां पहुंचा तो

FUSION/RAJ/4

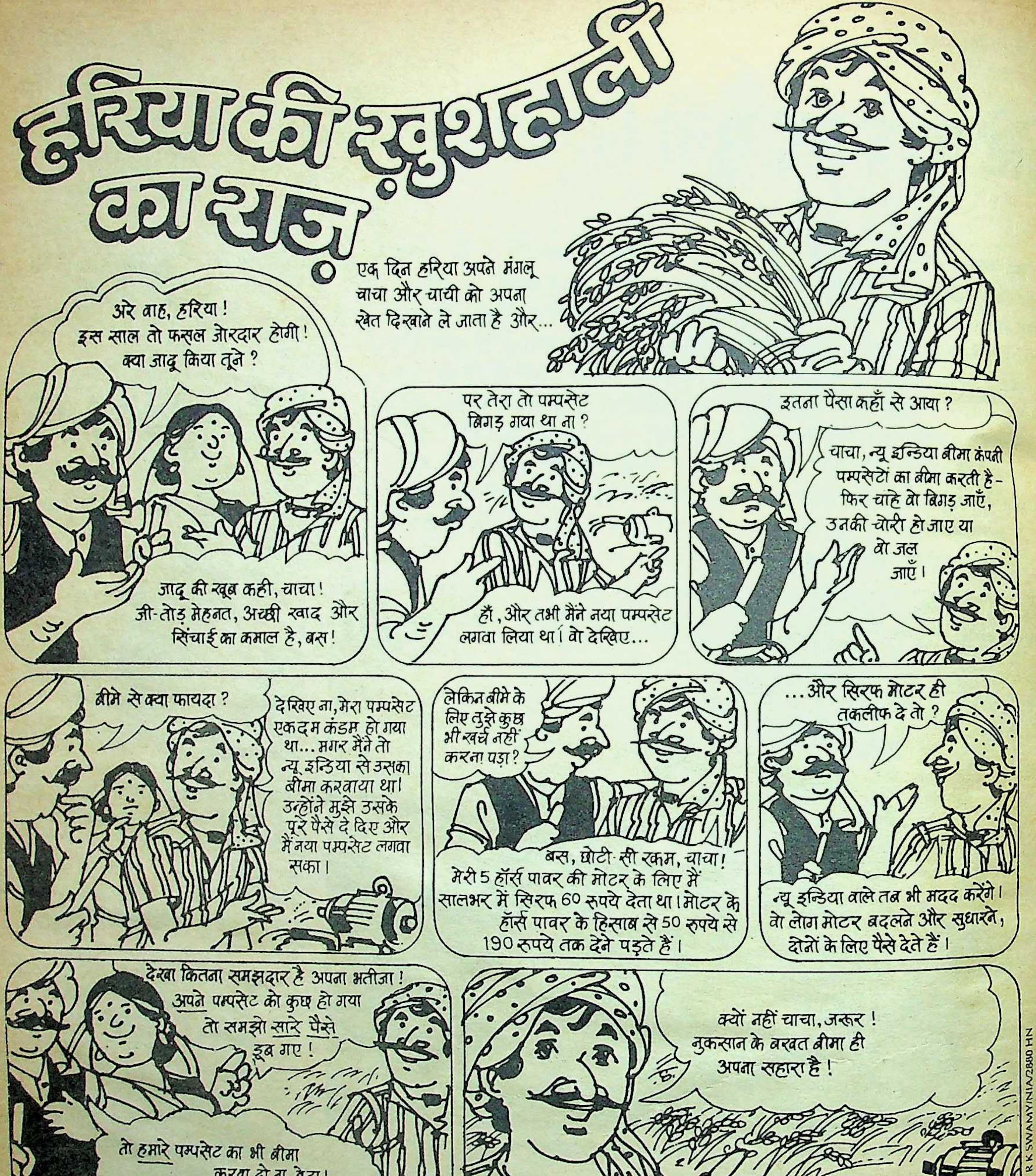
हरिया की ख़ुशहाली का राज़
एक दिन हरिया अपने मंगलू चाचा और चाची को अपना खेत दिखाने ले जाता है और...
अरे वाह, हरिया! इस साल तो फसल जोरदार होगी! क्या जादू किया तूने?
जादू की खूब कही, चाचा! जी-तोड़ मेहनत, अच्छी खाद और सिंचाई का कमाल है, बस!
पर तेरा तो पम्पसेट बिगड़ गया था ना?
हाँ, और तभी मैंने नया पम्पसेट लगवा लिया था। वो देखिए...
इतना पैसा कहाँ से आया?
चाचा, न्यू इन्डिया बीमा कंपनी पम्पसेटों का बीमा करती है-फिर चाहे वो बिगड़ जाएँ, उनकी चोरी हो जाए या वो जल जाएँ।
बीमे से क्या फायदा?
देखिए ना, मेरा पम्पसेट एकदम कंडम हो गया था... मगर मैंने तो न्यू इन्डिया से उसका बीमा करवाया था। उन्होंने मुझे उसके पूरे पैसे दे दिए और मैं नया पम्पसेट लगवा सका।
लेकिन बीमे के लिए तुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा?
बस, छोटी-सी रकम, चाचा! मेरी 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए मैं सालभर में सिरफ 60 रुपये देता था। मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से 50 रुपये से 190 रुपये तक देने पड़ते हैं।
...और सिरफ मोटर ही तकलीफ दे तो?
न्यू इन्डिया वाले तब भी मदद करेंगे। वो लोग मोटर बदलने और सुधारने, दोनों के लिए पैसे देते हैं।
देखा कितना समझदार है अपना भतीजा! अपने पम्पसेट को कुछ हो गया तो समझो सारे पैसे डूब गए!
तो हमारे पम्पसेट का भी बीमा करवा दो ना, बेटा!
क्यों नहीं चाचा, जरूर! नुकसान के वखत बीमा ही अपना सहारा है!
R K SWAMY/NIA/2880 HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इन्डिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

बीमा—नुकसान में आपका सहारा!

जनरल इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया की एक सहायक कंपनी

जार्ज ओगिल्वी ने दीवार पर टंगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या आप नवाब आफ पटौदी के बारे में जानते हैं। इस पर तो मैं तपाक से शुरू हो गया और क्रिकेट तथा टाइगर पटौदी के बारे में मालूम सारी जानकारी उगल दी। ओगिल्वी सुनते रहे फिर बोले, मैं उनके पिता इफ्तिखार अली खान के बारे में पूछ रहा हूं। मुझे काटो तो खून नहीं।

"बाद में ओगिल्वी ने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि यह कोई क्रिकेट की परीक्षा नहीं है। लेकिन कला ही असली परीक्षा होगी। अशोक का कलाकार मन तो इसके लिए तैयार ही था। फरवरी १९८४ से इसकी शूटिंग शुरू हुई। पहले एक महीने तो हमें मेलबोर्न तथा सिडनी के विशाल क्रिकेट स्टेडियमों में खेलाकर क्रिकेट में दक्ष किया गया।"

याद ताजा करते हुए अशोक कहते हैं, "उस समय वहां वेस्टइंडीज, आस्ट्रेलिया तथा पाकिस्तान के बीच तीन देशों की एक दिवसीय श्रृंखला हो रही थी। हमें ले जाकर वहां खेल दिखाया गया और बाद में 'बाडी लाइन' के वास्तविक हीरो जान ब्रैडमैन से मिलाया गया, जिन्होंने हमें उस समय के कुछ रोचक किस्से बताये। इसी सिलसिले में हमें इमरान खां तथा रिची बेनो सहित सभी टेस्ट स्टारों से मिलवाया गया।

'बाडीलाइन' के एक दृश्य में कप्तान डगलस जार्डिन (ह्यूगो वीविंग) के साथ टीम की रणनीति तय करते नवाब पटौदी (अशोक बांठिया)

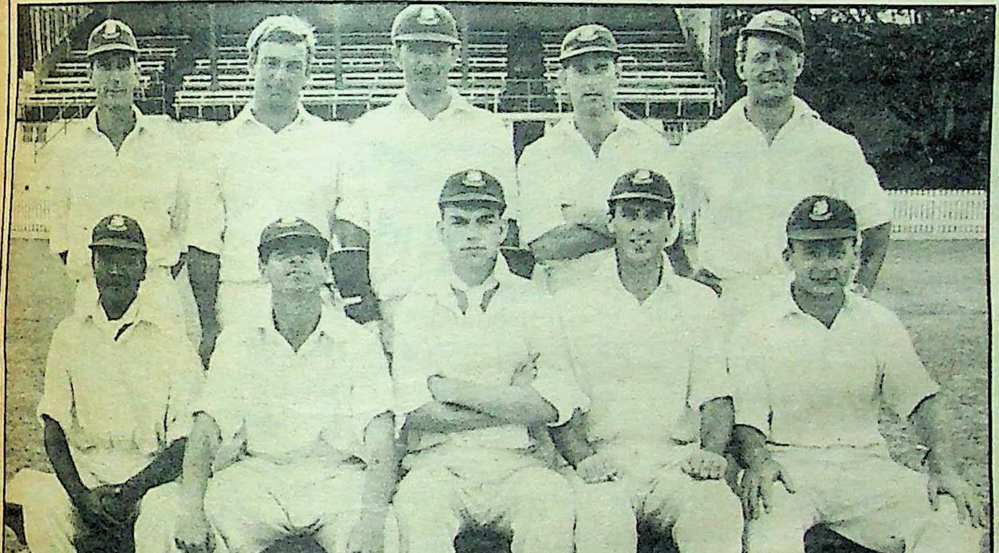
'बाडीलाइन' टी०वी० श्रृंखला की इंग्लैंड टीम। स्कार्फ बांधे (बैठे हुए) जार्डिन (ह्यूगो), एकदम बायें बैठे हुए नवाब पटौदी (अशोक)

"आपको पता ही होगा कि जार्डिन का जन्म भारत में हुआ था इसलिए नवाब पटौदी तथा जार्डिन में कुछ ऐसा भावनात्मक लगाव था कि वे अकसर साथ रहते और इत्तफाक देखिये कि वैसा ही संबंध मेरे और जार्डिन का रोल निभानेवाले ह्यूगो वीविंग के बीच बना।" इस पर अशोक अपने निचले होंठ का हिस्सा दिखाते हुए कहते हैं, "यह है हमारी बाडी लाइन की दक्षिणा, मैच के दौरान सचमुच में गेंद लग जाने के कारण यह होंठ ही फट गया था। यह मेरी एक यादगार धरोहर है।" अशोक जितने दिन यूनिट के साथ रहे सभी उसे 'नवाब' ही कहकर पुकारते थे। मई, १९८४ में इस श्रृंखला की शूटिंग पूरी हुई। अंतिम दिन की याद करते हुए अशोक की आंखों में पानी तैर उठता है "हर रात को हम यूनिट वाले दिन की शूटिंग की 'रशेश' भी देखते थे। उस दिन 'रशेश' चल ही रही थी कि एकाएक प्रिंट बीच ही में रोक दी गयी और निर्देशक ओगिल्वी ने उठकर कहा, "टूमारो नवाब इज लीविंग अस' (कल नवाब हमें छोड़कर चले जायेंगे)। उनका यह कहना था कि कुछ क्षणों के लिए स्तब्धता छा गयी। तब मैं जान पाया कि कुछ महीनों में हम पूरी यूनिट वाले कितने करीब आ गये थे।

बीकानेर में जन्मे और एक लकड़ी के व्यापारी के बेटे अशोक बांठिया में रंगमंच के गुण बचपन से ही थे, इसलिए उन्होंने स्कूल और कालेज की पढ़ाई पूरी होते ही घर छोड़ दिया और चले आये चंडीगढ़। यहां पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय रंगमंच विभाग में एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अशोक ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एन०एस०डी० दिल्ली) से रंगमंच में डिग्री प्राप्त किया। वह दिल्ली में स्कूल के प्रिंसिपल बी०एम० शाह के योगदान को अपने जीवन का शिल्पकार मानते हैं।

आस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अशोक ने 'नासूर' सहित कई फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं कीं और बाद में प्रसिद्ध निर्देशक गोविंद निहलानी के सहायक बन गये। उनके सहायक के रूप में अशोक ने 'आघात' तथा 'तमस' फिल्में कीं। दोनों फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक रहते हुए अशोक ने भूमिकाएं भी कीं। एन०एस०डी० के अपने पूर्व साथियों आलोकनाथ, नीना गुप्ता, दीपा साही, पंकज कपूर, अन्नू कपूर की तरह वह भी रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी खुद की गैरपेशेवर कलाकारों की एक संस्था 'गम्मत' नाम से चलती है। आजकल वह मद्रास में 'हंसा विजन' के टेलीविज़न सीरियलों में व्यस्त हैं।

'बाडी लाइन' उनके सक्षम कलाकार जीवन को एक नयी जिंदगी प्रदान करेगी, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है।

—बंबई ब्यूरो

दशहरा, दुर्गापूजा व दीपावली के पुनीत पर्वों पर

परम्परागत व आधुनिक डिज़ाइनों, सौम्य रंगों
से युक्त, परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण, सस्ते एवं टिकाऊ

यूपिका

के मनमोहक वस्त्रों पर

20 + 15 = **35%** की
रिबेट डिस्काउन्ट

विशेष छूट

27 सितम्बर से
देश व प्रदेश में स्थित यूपिका के सभी
बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध

राज किशोर मिश्र
प्रबन्ध निदेशक

श्रीमती प्रेमवती तिवारी
विधायिका (अध्यक्ष)

यूपिका हैण्डलूम्स
UPICA HANDLOOMS
KRISHNA

यू.पी. इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि.
117/418, सर्वोदयनगर, कानपुर

ब्रह्माण्ड का स्वप्ननाट्य और देवी का महिषासुरमर्दिनी रूप

कीर्तिमुख उपाख्यान के अनुसार देवता का क्रोधावेग दैत्य या असुर का रूप भी धारण कर सकता हैं। भारतीय पुराण-कथाओं में ऐसे असुरों के अनेक प्रसंग हैं। शिव का ध्वंसलीलाकारी रूप 'रुद्र' के नाम से जाना जाता है। देवी का क्रोध एक क्षुधार्त लोलुप व्याघ्र या सिंह में रूपांतरित हो सकता है। इसीलिए देवी को भयंकर काली के रूप में भी देखा जाता है। रणक्षेत्र में वह मानव का संहार करती हैं। विश्वमाता का यह विध्वंसकारी रूप है। इसी तरह किसी अभिशाप को भी मूर्त रूप देने के प्रसंग सम्भव हैं। वेदोत्तर युग की एक प्रसिद्ध पुराण-कथा है वृत्र-संहार गाथा। देवराज इन्द्र ने वृत्र का संहार कर घोर पाप किया था, क्योंकि वृत्र ब्राह्मण थे, इसलिए उस असुर ने देवराज इन्द्र को उनके अपराधजनित अभिशाप को मूर्त रूप देने के लिए अभियुक्त के रूप में उपस्थित किया है।

वृत्र के अंगच्छेदन के फलस्वरूप वह एक से अनेक रूपों में प्रकट हुआ, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसे इन्द्र और देवगण का प्रकृत पाप (किल्विष) कहा जाता है। इसके प्रायश्चित का मार्ग है विखंडित को अखंड रूप में लाना। बलिदान में आवर्तन और विवर्तन, दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जो एक प्रथा के रूप में दृष्टिगोचर अथवा किसी के जीवन में मानसिक रूप में भी घटित हो सकती हैं।

स्वयं देवी के प्रथम आविर्भाव से उत्पन्न बाह्य प्रकाश को 'देवी माहात्म्य' के मंत्र के रूप में उच्चारण किया जाता है। इस मंत्र में देवी अजेय रणरंगिणी के रूप में हैं, जो देवताओं के एकत्र क्रोध से प्रकट हुआ था, जो महिषासुर नामक असुर का संहारक बना। यह स्वेच्छाचारी असुर पृथ्वी का ध्वंस करने के लिए उत्पन्न हुआ था। उस समय विष्णु या शिव कोई नहीं थे। महिषासुर नामक उस असुर की आकृति भी विशाल महिष जैसी थी। इस दुर्दांत असुर से पीड़ित देवताओं ने ब्रह्मा के नेतृत्व में विष्णु और शिव के समीप जाकर अपनी असहाय स्थिति का वर्णन किया। इससे विष्णु और शिव क्रुद्ध हुए। दूसरे देवताओं का क्रोध और घृणा भी पुंजीभूत हुई। उनके मुख से शक्ति की लौ प्रकट होने लगी। विष्णु, शिव और अन्य देवतागण अपनी-अपनी शक्ति को प्रकट करने लगे। केन्द्रीभूत वह शक्ति अग्नि बन गयी। फिर वह अग्नि भयंकर मेघाग्नि की तरह प्रज्ज्वलित होकर अधिक तेजोमयी बनने लगी। उसके बाद अष्टादशभुजा देवी का रूप प्रकट हुआ।

ब्रह्माण्ड की परमाशक्ति का वह मूर्त रूप और अपनी-अपनी शक्ति का केन्द्रीभूत प्रकाश देखकर देवतागण आनन्दित हो उठे और उन्होंने अपनी सम्मिलित आशा के रूप में उनकी पूजा की। उनमें त्रिपुरसुन्दरी के विचित्रतापूर्ण व्यक्तित्व और क्षमता का समावेश हुआ। यही रूप सर्वशक्तिमत्ता का परिचायक है। इसके बाद देवताओं ने अपनी शक्तियां आदिरूप परमाशक्ति को लौटा दीं। ब्रह्माण्ड जब पहली बार विभिन्न क्षेत्रों और शक्तियों में विभाजित होने लगा था, तब प्राण शक्ति भी अगणित व्यक्तियों में संचारित हुई। लेकिन वे भी अपनी सारी शक्तियां खो बैठे, क्योंकि उनकी मातृरूपा आदिशक्ति ने उन शक्तियों को आत्मसात कर लिया था। इस प्रकार वे अपने पूर्ण अस्तित्व में विराजित हुई।

'देवी माहात्म्य' की और एक व्याख्या परम्परागत देवी प्रतिमा की पृष्ठभूमि में चित्रित आकृतियों में मिलती है। उनमें विभिन्न देवताओं को स्वेच्छा से शक्ति-त्याग की मुद्रा में अपनी राजोचित, नायकोचित और पुरुषोचित शक्ति का प्रयोग असुर-संहार में करते दिखाया जाता है। परमा देवी के हाथों वे अपने विभिन्न अस्त्र सौंपते हुए चित्रित किये जाते हैं। वे अपने सभी अलंकारों और प्रतीकों को, जिनमें उनकी शक्ति और विशिष्टता निहित होती है, त्यागते हुए दिखाये जाते हैं। जिस सर्वव्यापी स्रोत से वे उत्पन्न हुए थे, उसी में अपनी-अपनी प्रकृति और क्षमता सम्मिलित कर देते हैं। देवी प्रतिमा के पीछे ऊपर बायें कोने में त्रिशूल ताने शिव चित्रित हैं। वहीं ऊपर दायें कोने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपना भिक्षापात्र और ज्ञान भण्डार वेद की पांडुलिपि सौंपते हुए दिखाये जाते हैं। वहीं अलग से विचित्र महाकाल देवी को ढाल और तलवार दे रहे होते हैं। उनके दायें देवी के जनक गिरिराज हिमालय खड़े दिखाये जाते हैं। उनके साथ सिंह होता है। देवी उसी सिंह को अपना वाहन बनायेंगी न!

भारत में भास्कर्य और मूर्तिकला की विभिन्न आंचलिक शैलियां प्रचलित हैं। लेकिन यह स्पष्ट देखा जाता है कि भास्करों और मूर्तिकलाकारों के लिए देवी का महिषासुरमर्दिनी रूप ही सर्वाधिक प्रिय है। बंगाल के मूर्तिकार सामान्य रूप से महिषासुरमर्दिनी का जो रूप प्रस्तुत करते हैं, वह सातवीं सदी की मामल्लपुरम की एक रिलीफ (उकेरी गयी मूर्ति) से लिया गया है। सूक्ष्मकार्य की दृष्टि से पल्लवकालीन यह शैली अतुलनीय है। पल्लवकाल की मूर्तियां तेजोद्दीप्त होती हुई भी शान्त हैं।

'देवी माहात्म्य' में कहा गया है, असुर सेना को छिन्न-भिन्न करने के बाद देवी ने महिषासुर की तरफ पाश फेंका। सिंह का रूप धरकर महिषासुर उस पाश से बच गया। देवी ने उस सिंह का शिरच्छेद किया। महिषासुर तब माया द्वारा असिधारी योद्धा बन गया। देवी उस पर बाण-वर्षा करती रहीं। लेकिन उससे असुर का कुछ भी न बिगड़ा। वह हाथी का रूप धारण कर अपनी सूंड से देवी को खींचने लगा। देवी ने तलवार से उस सूंड को काट डाला। असुर फिर विशाल भैंसा बनकर अपने खुरों के आघात से धरती कंपाने लगा। देवी ने अट्टहास किया। फिर वह क्रोध से भरकर गरज उठीं। उसके बाद क्षण भर रुक कर उन्होंने दैव प्राण शक्ति रस से भरा पात्र होंठों से लगाया। उस अतुलनीय रसपान से उनके नेत्र रक्तवर्ण हो गये। उधर महिषासुर अपने सींगों से पर्वत उखाड़-उखाड़कर देवी की तरफ फेंकने लगा था। देवी ने उच्चस्वर में कहा, "मूर्ख चिल्लाता रह! मैं यह सुमधुर सुधारस पी लूं। उसके बाद तेरा शव मेरे

When you are searching Your interest areas in an English magazine....
....Take a look at PROBE INDIA

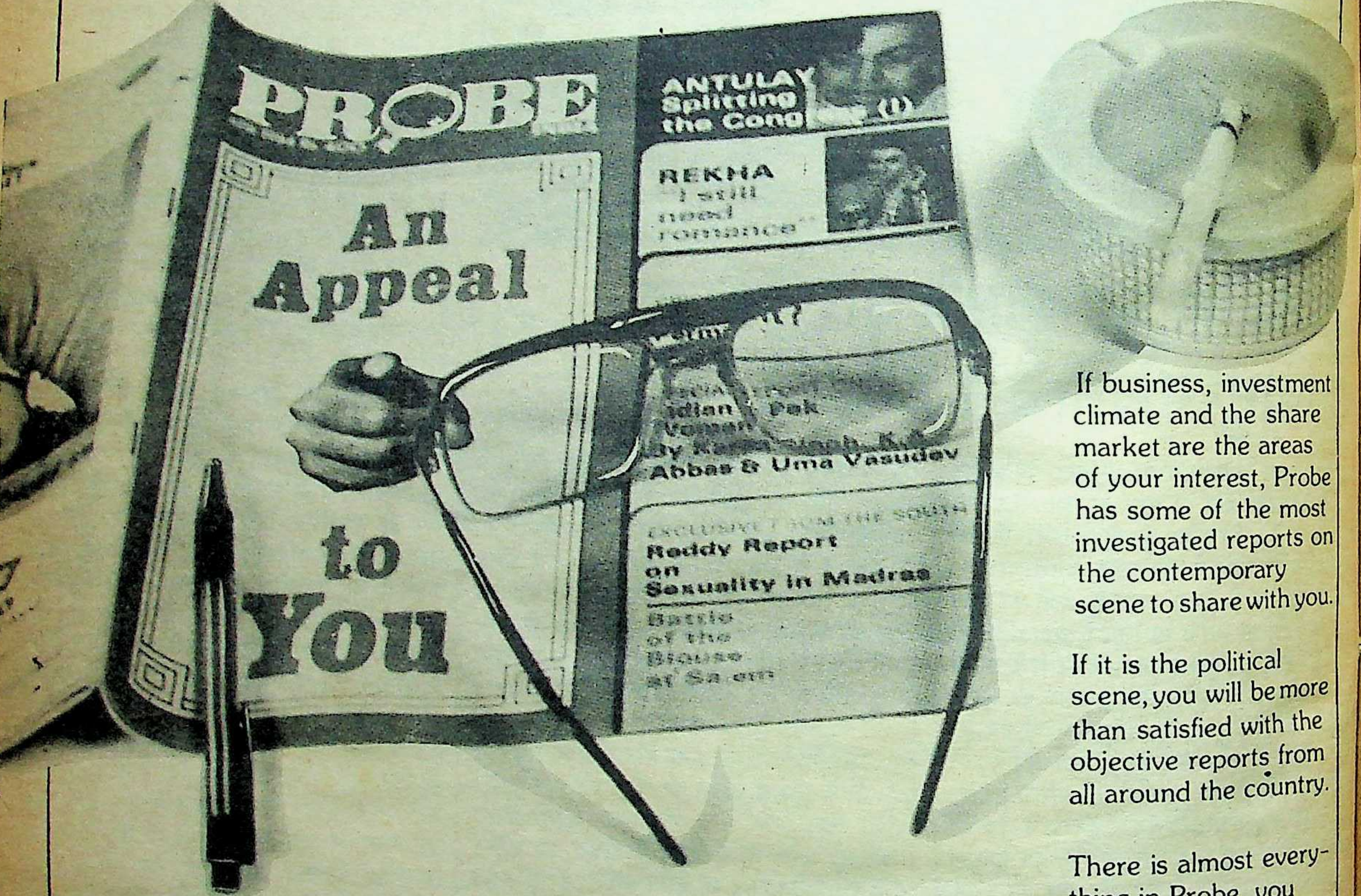
PROBE
An Appeal to You
ANTULAY Splitting the Cong... (1)
REKHA "I still need romance"
Abbas & Uma Vasudev
Reddy Report on Sexuality in Madras
Battle of the Blouse at Salem

If business, investment climate and the share market are the areas of your interest, Probe has some of the most investigated reports on the contemporary scene to share with you.

If it is the political scene, you will be more than satisfied with the objective reports from all around the country.

There is almost everything in Probe, you could look for-sports, cinema, media, focus on international scene, women, lifestyle, human interest and regional coverages.

And for your leisure you have the visual delight of photo-features.

Probe is an interesting and bold blend of topical coverage with an insight into the future, for we take a stand on controversial issues.

PROBE
INDIA
Reporting with credibility that's seeded within.

ag
n
NDIA
stment
share
reas
Probe
most
orts on
ry
th you.
al
more
h the
from
untry.
every-
ou
focus
tyle,
ges.
sual
nd of
o

पांवों के पास पड़ा रहेगा और देवतागण आनंद से भरकर चिल्ला पड़ेंगे।''

उसके बाद देवी उछलकर असुर की गरदन पर पहुंच गयीं। उन्होंने उसे धरती पर गिराकर त्रिशूल उसकी गरदन में घोंप दिया। महिषासुर ने फिर असिधारी योद्धा का रूप धरना चाहा। वह उस रूप में आधा रूपांतरित भी हुआ, लेकिन देवी ने उसका मुंड काट डाला।

इस अद्‌भुत रूपांतरण की गाथा शक्ति के बाह्य प्रकाश का विशिष्ट पौराणिक उदाहरण है। महिषासुर ने माया का प्रयोग कर अपनी प्राणशक्ति को नये-नये रूपों में प्रकट किया। ये सभी रूप शक्ति के बाह्य प्रकाश के द्योतक हैं। शिव के क्रोध ने कीर्तिमुख का रूप ले लिया था।

शरीर और आत्मा की प्राण शक्ति जब उद्दीप्त होती है, तब वह अपकारी या उपकारी, आसुरिक या दैवी, किसी भी रूप में प्रकाशित हो सकती है। यह कार्य-कारण की प्रकृति पर निर्भर करता है। ब्रह्माण्ड के रणक्षेत्र इन देवताओं से पूर्ण हैं। लेकिन उनमें शक्ति के बाह्य प्रकाश की प्रवणता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्माण्ड स्वयं परमा शक्ति का एक रूपांतर है। शिव को लिया जाये, तो उनकी प्राण शक्ति उनकी अंकशायिनी शक्ति है। विष्णु को लिया जाये, तो उनके महाजागतिक स्वर्ण कमल का व्यक्तित्वारोपित अंग ही देवी है। विष्णु के इस स्वर्ण कमल से विवर्तन शुरू होता है। इससे विश्व प्राणियों से भर जाता है। यह शक्ति का ही रूपान्तर है। अर्धशायित विष्णु ने महाशून्य का निर्माण कर ब्रह्माण्ड के नियमानुसार उसे परिपूर्ण किया। वह उनकी कमलनाभि पर अधिष्ठित शक्ति का प्रकाश मात्र हैं। भगवान विष्णु के स्वप्न का रूपायन ही विश्व विधान है।

यानी, हम कोई देवता नहीं, सीमित अस्तित्व मात्र हैं। हमारी मूल प्राण शक्ति का अनवरत बाह्य प्रकाश ही हमारा 'क्षुद्र ब्रह्माण्ड' है। हम अपनी अन्तर्निहित आत्मा के स्वप्न के चित्र-प्रवाह को एक निष्पक्ष परदे पर प्रतिफलित होते देखते हैं। और उस नाटकीय घटनाक्रम के शिकार होते हैं। संसार को हम जिस रूप में देखते और समझते हैं, वह ठीक उसी रूप में नहीं है। वह हमारी माया अथवा भ्रान्ति का परिणाम है। वह हमारी अंध प्राण शक्ति है, जो असुर अथवा मंगलमय रूप को 'उपस्थित करने में सक्षम है। इसलिए हम अपनी माया के प्रभाव से अबद्ध रहते हैं। जब भी हम जैव कामना-वासना में लिप्त होते हैं, तब उसमें हमारे अंदर की सारवस्तु का ही प्रतिफलन होता है। यही है माया का सम्मोहन।

क्रुद्ध और युद्धरत देवताओं के आकार-प्रकार दर्शन, पराविद्या और मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि के परिचायक हैं। जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वहीं माया के स्वामी हैं। अन्यान्य सुर, असुर और मानव अपनी-अपनी माया के शिकार हैं। हमारी प्राण शक्ति हमें मूढ़ता, कामना-वासना और बद्ध संस्कार में लिप्त रखती है। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम माया के क्रीत दास हैं। यदि ऐसा न होता, तो हम व्यक्ति के रूप में परिचित न होते, हमारा कोई इतिहास न रहता, जीवनवृत्त न बनता। हमारे व्यक्ति जीवन का सार ही जीवन के बारे में भ्रान्ति या मोह है।

देवराज इन्द्र भी अपनी व्यक्तिगत माया द्वारा परिचित होकर अपने को देवताओं के राजा के रूप में चिह्नित करने को विवश हुए थे। इसीलिए सभी महान भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य को माया की दासता से मुक्त करने का प्रयास किया है। जो पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तन मानव-भावना को बुद्धिग्राह्य दृष्टिकोण से विचार करने को प्रेरित करता है, उसकी परम विशिष्टता को भी ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय प्रज्ञा, जो योग के अनुभव पर आधारित है, मानवी प्रकृति में समग्र रूपान्तरण लाना चाहती है।

भारतीय पुराण और दर्शन की तरह भारतीय शिल्पकला में भी यही सत्य प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह सत्य भी मानवशक्ति को रूपान्तरण की उसी दिशा में ले जाना चाहता है। इसीलिए भारतीय पुराण और प्रतीक के छात्र के रूप में हमारा कर्तव्य है—भारतीय दार्शनिक चिन्तन का बुद्धिग्राह्य दृष्टिकोण से अनुशीलन करना तथा भारतीय शिल्प के प्रतीक में, मूर्तियों के आकार-प्रकार में कौन-सा रहस्य छिपा हुआ है, उसको उद्घाटित करना। ऐसे प्रतीकों में ही भारत की सनातनी परमा प्रज्ञा का चित्रमय वर्णन मिलता है।

हम प्रायः देखते हैं कि मंदिर की दीवारों पर और विभिन्न शिल्प-कार्यों में देवी के विभिन्न रूप हैं। कहीं उनके आठ हाथ हैं, तो कहीं दस। लेकिन उनके प्रामाणिक आदि रूप में अट्ठारह हाथ हैं। भारत के विभिन्न भागों में उनके विभिन्न रूप मिलते हैं। बंगाल में प्रचलित रूप में उनके दस हाथ हैं। देवी जब महिषासुर का वध करती हैं, तब उस अद्‌भुत मुद्रा में कौन-सा भाव निहित है, उसको सबसे पहले देखना होगा। दसवीं सदी में खजुराहो के चन्देलों के लोक शिल्प को बंगाल से प्रेरणा मिली थी, ऐसा अनुमान किया जाता है। निष्ठुरता और हिंसा को उसमें संयत रूप में दिखाया गया है। नाटकीय पराकाष्ठा की स्थिति को भी शांति और महानता के रूप में सोचा गया है। संवेदनशीलता भी आध्यात्मिक आनंद की प्रतिच्छवि बन गयी है। महिषासुर का भयंकर रूप भी भय का उद्रेक नहीं करता। वह कोई मूढ़मति, वशीभूत जीव लगता है।

बंगाल के शिल्पकार जिस प्राचीन मूर्ति-कल्पनाको मृण्मय रूप देते हैं, उसमें देवी को असुर के बाल पकड़कर उस पर अंतिम आघात करते दिखाया जाता है। विश्व की रक्षा के लिए वैसा वीरोचित आघात करना आवश्यक है, लेकिन वहां भी क्रोधोन्मत्त आवेश की विशेषता अनुपस्थित रहती है। देवी को शाश्वत शान्ति और नीरवता से मण्डित दिखाया जाता है। काल और महाशून्य की सभी क्रियाएं सम्पन्न होने को बाध्य हैं, फिर भी देवी की निर्विकार मुखमुद्रा मानो उनके गुरुत्व को न्यून करती है। उनके लिए विश्व-ब्रह्माण्ड की सभी क्रियाएं महाजागतिक स्वप्न के अंश मात्र हैं। यहां तक कि उनकी अपनी प्रतिच्छवि भी वैसी दिखायी पड़ती है, जबकि वह रक्षक की भूमिका में अवतरित हैं। यही है माया का चिरन्तन प्रकाश और उसकी विशिष्टता। यद्यपि परम दैवी अस्तित्व के रूप में देवी अलग रूप धारण कर विश्व ब्रह्माण्ड के स्वप्ननाटक में एक भूमिका निभाती हैं और उस नाटक के चूड़ान्त दृश्य में एक प्रधान पात्र के रूप में उनका आचरण होता है, तथापि उस आचरण से ऐसा लगता है कि उनके मनोजगत में कोई वीर नायक प्रतिष्ठित है। परंतु मौलिक रूप से सचेतन होकर देखने पर जान पड़ेगा कि देवी के विजयी रूप से वीर नायक का वह रूप संबद्ध नहीं है। उनका परमसुंदर क्षमामण्डित मुखमण्डल तेजस्विता से परिपूर्ण है। वह आत्मभूत प्रशान्त भाव में मग्न हैं। अतीव शक्तिसम्पन्न होते हुए भी देवी की मुखमुद्रा अतीव प्यारी है।

देवी की दृष्टि संहार के उस पार क्यों?

आंखें देखकर ऐसा लगता है कि देवी बिन्दु अर्थात माया की प्रतिच्छाया हैं और आनंद या वेदना की अंतर्क्रिया के अनुभव के बारे में उदासीन। ब्रह्माण्ड का नियम मानो वह नहीं जानतीं। मानवीय चेतना में प्रतिफलित व्यक्ति-जीवन के बारे में भी मानो उनमें कोई आग्रह नहीं है। सुख-दुखं में वह निर्विकार हैं। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं अथवा औद्धत्य की संहारक के रूप में भी मानो वह सचेतन नहीं हैं। मानो उनकी आंखों से संहार लीला का सारा दृश्य मिट चुका है। संहार के उस पार उनकी आंखें मानो असीम के क्षितिज पर टिकी हुई हैं। उन आंखों में महाजागतिक दृष्टि है। कालप्रवाह की सीमा के अंदर छिन्न-विछिन्न घटनाओं का शाश्वत में कोई स्थान नहीं है। वे सब सृष्टियां भाप की तरह होती हैं, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती हैं। परंतु माया के प्रभाव से जो कुछ घटित होता है, जैसे ब्रह्माण्ड अथवा व्यक्ति, वह सब दृश्यमान है। यह दृश्यमान होना या घटित होना कैसा है? देवी की मुखमुद्रा से इसका उत्तर मिलता है। वह यह है कि शाश्वत सत्य के आगे कुछ भी घटित, कुछ भी लुप्त और कुछ भी परिवर्तित नहीं होता। कुछ भी वाष्प का रूप नहीं लेता। दैव ही एकमात्र सार वस्तु है, जो यथार्थ है। इस कारण परम (ब्रह्मन्) स्वयंसम्पूर्ण, अपने ही प्राचुर्य से पूर्ण, अपनी ही शून्यता से रिक्त, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है।

अन्त में, माया है क्रमबद्ध आत्म-बाह्य प्रकाश और ब्रह्मन् का आत्म-छद्मवेश। इसका आत्मप्रकाश और इसका अनेक रंगों वाला आवरण सहावस्थान कर सकते हैं। समस्त नश्वर वस्तुओं में वह उत्कर्ष का संचार करता है। इसलिए इनके एकत्रीभूत रूप अर्थात समष्टि की परमा देवी के रूप में पूजा होती है। वही मातृ रूपा और देवगण की प्राण शक्ति (शक्तिरूपेण) है। माया-शक्ति देवी के नियमानुसार सभी प्राणी परिचालित होते हैं। वह सर्वोत्तम और सर्वशक्ति सम्पन्न हैं। श्री श्री चण्डी में उन्हीं का रूपचिन्तन तथा अनुध्यान है:

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमः नमः।

—आलोक मित्र

जब ब्लैक कैट ने दांत कटकटाये

१० सितम्बर को अपराह्न, दिल्ली दरबार, दरबारिन के साथ जब अपनी रियाया (अमेठी के मतदाता) का हालचाल पूछने के उद्देश्य से फुरसत-गंज की जमीन पर उतरा, तो हवाई अड्डे पर कड़ी नाकेबंदी थी।

लेकिन ११ सितम्बर की दोपहर, टीकरमाफी आश्रम में ब्लैक कैट असहाय होकर बस दांत कटकटाती रही। उसे दरबार पर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि उसने 'प्रसाद' के लड्डू और काजू बिना ब्लैक कैट को चखाये खुद क्यों खा लिए? हुआ यह कि दिल्ली दरबार घूमता-फिरता टीकरमाफी आश्रम जा पहुंचा। पहुंचते ही दरबारिन के साथ उसने स्वामी परमहंस सरस्वती की समाधि पर माथा टेका। समाधि-परिसर में जाते समय दरबार और दरबारिन जूते-सैंडिल उतारना नहीं भूले। समाधि से बाहर आकर वे दोनों आश्रम के एक स्वामी, शान्तानंद के सामने पहुंचे और साष्टांग दण्डवत किया। तब स्वामीजी ने अपने चेलों को आदेश दिया, "दरबार को प्रसाद लाकर खिलाओ।" दो चेले दौड़कर आश्रम के एक कमरे में गये तथा थाली में कुछ लड्डू और प्लेट में काजू ले आये। थाली-प्लेट, दरबार-दरबारिन के सामने कर दी गयी। दोनों ने एक-एक लड्डू और कुछ काजू उठाये और मुंह में डाल लिया। ब्लैक कैट उसे चखने के लिए दौड़ी, तब तक काजू-लड्डू मुंह के अन्दर पहुंच गये थे। ब्लैक कैट, दांत कटकटाकर रह गयी। बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी, लेकिन इसके बाद ही दरबार ने बिना ब्लैक कैट के मुंह पर छींटा मारे सामने रखे ग्लास का पानी हलक से नीचे उतार लिया।

इसके बाद आश्रम के प्रमुख स्वामी चैतन्य ब्रह्मचारी के साथ दरबार, पूजा के कमरे में घुस गया। दरबारिन तो साथ थीं, लेकिन ब्लैक कैट को डाटकर भगा दिया गया। कमरा अन्दर से बंद हो गया। आधे घंटे तक दरबार और दरबारिन बंद कमरे में क्या करते रहे, यह केवल स्वामीजी ही जानते हैं। लेकिन आश्रम के चेलों का कहना था, "स्वामीजी, दोनों से उस अनुष्ठान का समापन करा रहे हैं, जो संजय सिंह के पार्टी से हटाये जाने के बाद स्वामीजी ने दरबार को दरबार में बनाये रखने के लिए शुरू किया था। चेलों के इस कथन की पुष्टि तब हुई जब कमरे से बाहर निकलने पर दरबार-दरबारिन के हाथ में ढेर सारा प्रसाद और फूलों की एक-एक माला थी। दोनों के माथे पर लम्बा टीका लगा था।

बताने वाले बताते हैं कि टीकरमाफी आश्रम और उसके स्वामी का अमेठी के कई इलाकों में खासा दबदबा है। लगभग बीस हजार का 'वोट बैंक' स्वामीजी के पास है।

धवन की ध्वनि

सितंबर की एक सुहानी रात की बात है। राजधानी के सबसे नये, सबसे महंगे और कुछ लोगों के अनुसार सबसे सुंदर पंचतारा होटल मेरिडियन के सबसे ऊपरी तल पर स्थित रेस्तरां में उस रात एक विशिष्ट अतिथि उपस्थित था।

उसके साथ दो मेहमान और थे—एक दंपती। आर्क्रेस्ट्रा के संगीत, मद्धम रोशनी और वेटरों की विनम्रताभरी सतर्क निगाहों के बीच भोजन समाप्त हुआ। तब तक रोचक घटना घटी। इससे पहले कि वेटर बिल लेकर आता, विशिष्ट व्यक्ति ने जेब से अपना बटुआ निकाला और सामने बैठी महिला को दे दिया। महिला ने जो कुछ वर्ष पहले अत्यंत कमनीय रही होगी, बटुए में से सौ-सौ के चार-पांच नोट निकाले और बटुआ लौटा दिया।

कुछ देर में बिल आया, महिला ने अपने पर्स में से वही नोट निकाले और बिल चुका दिया। उनका पति शांत भाव से यह कार्रवाई देख रहा था। और फिर तीनों बड़े सहजभाव से टहलते हुए चल दिये।

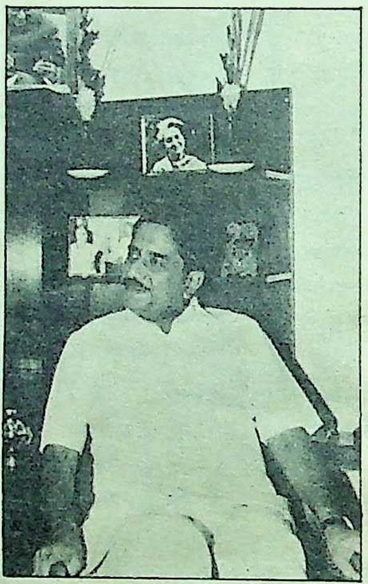

विशिष्ट व्यक्ति थे आर॰के॰ धवन। आर॰के॰ धवन जिनका रहस्यमय मौन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी सुनाई पड़ता है कि कुछ बड़े भारतीय और विदेशी प्रकाशक उनको अपनी आत्मकथा या श्रीमती गांधी के संग बिताये वर्षों के संस्मरणों पर पुस्तक लिखने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी रकम का प्रलोभन दे रहे हैं। कभी यह सूचना आती है कि फोतेदार और अरुण नेहरू के हट जाने के बाद धवन की प्रधानमंत्री निवास में वापसी होने ही वाली है। इन तरह-तरह की अफवाहों में एक ही बात की पुष्टि हुई है। ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने के इरादे से विरत करने में धवन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। किंतु स्वयं धवन गोल्फ लिंक्स के अपने घर के एकांत में चुपचाप जी रहे हैं—एक प्रश्न बने हुए।

अब गोपी अरोड़ा

माखन लाल फोतेदार का केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने के बाद प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार की जगह गोपी अरोड़ा ने संभाल ली है। गोपी अरोड़ा अपने विशेष सचिव के काम के अलावा राजनीतिक कामों में राजीव गांधी को सलाह देने लगे हैं। इंका मुख्यालय में बैठने वाले महामंत्री पहले फोतेदार से निर्देश लेते थे। फोतेदार इंका की निवर्तमान प्रवक्ता नजमा हेपतुल्ला से काफी नाराज रहते थे। इसीलिए उनको 'प्रेस' को देने के लिए कुछ नहीं बताते थे। अब इंका के नये प्रवक्ता गुलाम नबी आजाद बनाये गये हैं।

इंका मुख्यालय, २४ अकबर रोड पर अब हर शाम ५ बजे राजीव गांधी के कमरे में गुलाम नबी आजाद आकर जम जाते हैं। बताया जाता है कि उसके पहले वह ३ से ४ बजे के बीच गोपी अरोड़ा से मिलने जाते हैं या फिर उनसे फोन पर बात करके पत्रकारों को दी जाने वाली 'ब्रीफिंग' लेते हैं। बताया जाता है कि गोपी अरोड़ा गुलाम नबी को बताते हैं कि आज शाम को उनको संवाददाताओं से क्या कहना है। कभी-कभी गुलाम नबी अपनी ओर से भी कुछ सुझाव देते हैं। अगर गोपी अरोड़ा उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर उस पर गुलाम नबी का बोलना मुश्किल होता है। गोपी अरोड़ा की—'ब्रीफिंग' गुलाम नबी नोट करके लाते हैं। वह एक-एक कागज निकालते हैं और शाम ५ बजे पत्रकारों को ब्रीफ करते हैं।

संस्थापक: स्वर्गीय श्री क्षितीन्द्रमोहन मित्र। सम्पादक: आलोक मित्र। श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा॰लि॰ के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा॰लि॰, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

सफलता का दसवाँ वर्ष
10
प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक
1978-1987

प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये आवश्यक
बौद्धिकता, मौलिकता
एवं
विषय-वस्तु की सम्पूर्णता

A~
30/10/87

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी [illegible]

भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु हिन्दी की प्रथम पत्रिका

प्रतियोगिता दर्पण
नवम्बर १९८७ मूल्य रु. ६.००
हिन्दी मासिक
'शिक्षित बेरोजगारों के स्वर्णिम भविष्य के लिये'
दीपावली अभिनन्दन
तमसो मा ज्योतिर्गमय

युवा वर्ग के समग्र विकास के लिये पत्रिका एक उद्देश्य अनेक

व्यक्तित्व विकास
चरित्र निर्माण
राष्ट्र सेवा

नवम्बर 1987
मूल्य : रु. 6.00

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

नवम्बर अंक के प्रमुख आकर्षण–

- नवीन विषयों पर परीक्षोपयोगी लेख
- राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं खेल-जगत पर स्मरणीय तथ्य
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षाओं से सम्बद्ध विशेष सामग्री
- सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, एन. डी. ए., सी. डी. एस., बैंक क्लर्क्स एवं प्रोबेशनरी ऑफीसर्स, एस. एस. सी. क्लर्क्स ग्रेड आदि परीक्षाओं पर एक-साथ महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन
- युवा प्रतिभाएँ (श्रेष्ठतम सफल प्रतियोगी का साक्षात्कार)
- रिलायन्स विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता पर विशेष लेख
- **साथ में सभी स्थाई स्तम्भ**

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा- 282 002
फोन : 61802, 63676

स्वाद भी पाए. बढ़ता भी जाए... मुन्ना फ़ैरेक्स® के साथ-साथ.

अपने शिशु का वज़न व क़द जाँचिये *	बेटा		बेटी	
	वज़न	क़द	वज़न	क़द
उम्र ३ महीने तक	५.२ कि.ग्रा.	५९.९ सें.मी.	४.९ कि.ग्रा.	५८.४ से.मी.
उम्र ६ महीने तक	६.७ कि. ग्रा.	६४.७ सें.मी.	६.१ कि.ग्रा.	६३.७ सें.मी.
उम्र ९ महीने तक	७.३ कि.ग्रा.	६८.२ सें.मी.	६.९ कि.ग्रा.	६७.० सें.मी.
उम्र १२ महीने तक	८.४ कि.ग्रा.	७३.९ सें.मी.	७.८ कि.ग्रा.	७२.५ सें.मी.

* इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किया गया.

भारतीय शिशुओं के लिए यह केवल एक औसत है, अगर आपका डॉक्टर शिशु के विकास से संतुष्ट है तो चिंता की कोई बात नहीं.

रंगीन 'बेबी केअर गाइड' पुस्तिका मुफ़्त मंगाने के लिए लिखिये :
ग्लैंडिया लि. (FPD/ 245),
डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली,
बम्बई-४०० ०२५.

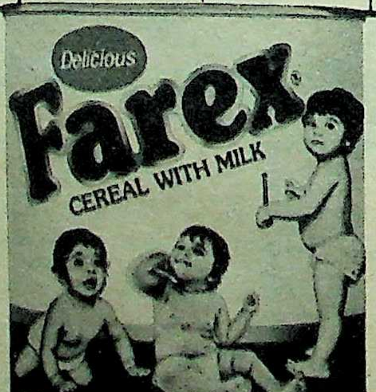

शिशु के चहुमुखी विकास और वृद्धि के लिए उसे पौष्टिकता से भरपूर आहार ''फ़ैरेक्स'' दीजिये.

फ़ैरेक्स®

शिशु बढ़े.फूले-फले...
जब फ़ैरेक्स मिले

CLARION/B/26/244 HIN

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक २०

अक्तूबर द्वितीय पक्ष, १९८७

माया

यह अंक

आवरण कथा

महेंद्र सिंह टिकैत एक अनपढ़ और देहाती व्यक्ति हैं, लेकिन किसान उन्हें अपना मसीहा समझते हैं। वह रातोंरात किसानों के ऐसे लोकप्रिय नेता बन गये हैं कि उनकी एक आवाज के साथ लाखों किसान एकत्र हो जाते हैं। क्या कारण है कि चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद किसानों ने किसी स्थापित नेता के बजाय अपने बीच से निकले टिकैत को अपने भविष्य का नियंता बना दिया है? २५

जनमोर्चा

वी०पी० सिंह ने काफी प्रतीक्षा के बाद 'जनमोर्चा' नाम से जो संगठन बनाया है, क्या वह एक शक्तिशाली राजनीतिक मच बन पायेगा? १९

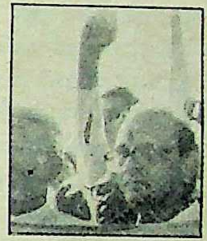

बिहार

इंका विधायक रामजतन पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि वह निर्दलीय विधायक कृष्णा सिंह के खून के प्यासे हो गये हैं?
४६

मध्य प्रदेश

वी०पी० सिंह को मध्य प्रदेश यात्रा में मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से प्रदेश कांग्रेस के खेमे में कैसा हड़कंप मच गया है? ७२

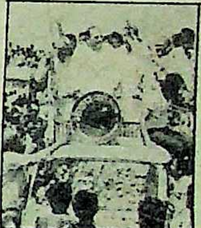

राजस्थान

सती विरोधी अध्यादेश जारी करने के बावजूद राजस्थान सरकार और विपक्षी नेता सती-प्रथा का जोरदार विरोध क्यों नहीं कर पा रहे? ४९

किशोर कुमार

करीब चार दशकों तक करोड़ों फिल्म प्रेमियों के दिलों पर राज करनेवाले किशोर कुमार की जिंदगी और कला का आकलन: ६३

उत्तर प्रदेश

नगर विकास राज्य मंत्री पद्मा सेठ पर उनके ही चुनाव क्षेत्र बिसवां के लोग किन ठेकों के कारण भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? ८५

दिल्ली दरबार: संघं शरणं गच्छामि! ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
फोटोफीचर ९
बेढब १३
रामधन से साक्षात्कार १४
आवरण कथा: टिकैत से बातचीत ३८
राडार: गल्फस्ट्रीम विमान क्यों खरीदा गया? ४२
राजस्थान: क्या लोकदल-ब कांग्रेस का विकल्प होगा? ५६
अभिमत: सुब्रह्मण्यम स्वामी: भारत में श्रीलंका का विलय अब एक मात्र रास्ता है ७०
फिल्म: मोहसिन खां से साक्षात्कार ७९
उत्तर प्रदेश: राज्य कर्मचारी क्या फिर हड़ताल करेंगे? ८२
कार्टून ९२
परदे के पीछे ९४
तथ्यकथ्य ९७
दूरदर्शन: 'आखिरी मुगल': शहंशाह की दास्तां ९८
अर्थतंत्र: क्या राजीव गांधी अपनी आर्थिक नीति बदल रहे हैं? १००
अचानक १०३
लोग १०४

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

आवरण पारदर्शी: मनमोहन शर्मा (टिकैत), डी०आर० यादव (किशोर कुमार)

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स: ०३१.६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

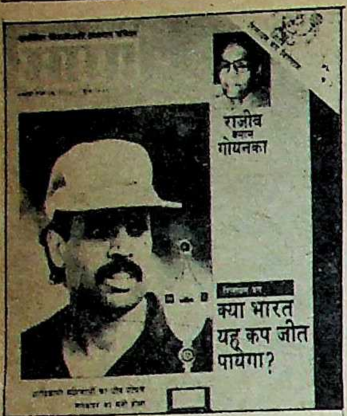

यदि वह प्रधानमंत्री न होते तो...

मैंने ३० सितंबर की 'माया' में, विशेष रिपोर्ट पढ़ी। मालूम हुआ कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के विकास एवं देखभाल के लिए विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के चार सदस्यों—प्रमोद तिवारी, पी० के० शर्मा, शिवबालक पासी एवं श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—को सीधी जिम्मेदारी देकर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस०पी० आर्य को भी अमेठी संसदीय क्षेत्र से संबद्ध कर दिया गया है। इसके बावजूद स्वयं राजीव गांधी एवं सोनिया गांधी हर तीसरे महीने अमेठी क्षेत्र के लोगों से मिलने और वहां हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए दौरा करेंगे। अमेठी के विकास में, सोनिया गांधी को सचल अस्पतालों के जरिये दवाओं के रूप में हो रहे दो लाख रुपए माहवारी खर्च के साथ-साथ वहां के औद्योगिक, सामाजिक एवं यातायात के विकास के नाम पर सरकार का अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के उपर्युक्त चार मंत्रियों एवं खुद प्रधानमंत्री के त्वरित आगमन पर उन लोगों की व्यवस्था में क्या उससे कम सरकारी धन का खर्च होगा? क्या देश की अन्य जनता के साथ यह भेद-भाव नहीं है। क्या इसे पद एवं सरकारी कोष के दुरुपयोग का मामला नहीं माना जा सकता? यदि वह प्रधानमंत्री न होते, तो क्या उनके लिए यह सब कर पाना संभव होता? शायद नहीं। यह भी प्रश्न उठता है कि क्या वह अकेले अमेठी संसदीय क्षेत्र के प्रधानमंत्री हैं? —रामशंकर पाठक, ग्राम-हिनौता, पोस्ट-करमा, मिरजापुर

महिला पुलिस को साधुवाद

३० सितंबर के अंक (अचानक) में नवगठित महिला पुलिस बल (सीआरपीएफ) की दो महिला कर्मियों द्वारा एक महिला पर दिखाये जा रहे 'पराक्रम' को देखकर बहुत खुशी हुई और राहत मिली कि चलो, अब हमारे देश की महिला पुलिस ने भी आतंकवाद कों समाप्त करने का नया रास्ता अपनाया है, आतंकवाद के खिलाफ एक महिला पर जोर आजमाइश करके और हमारे देश के कर्तव्यपरायण पुरुष (पुलिस) इस काम में महिला पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, बेशर्मी से दांत दिखाकर। शायद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इसे पुलिस द्वारा संपन्न शानदार काम समझते हैं, इसीलिए सदन में यह वक्तव्य देते नहीं थकते कि पुलिस ने महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया।—कु० किश्वर अंजुम, रायपुर, मध्य प्रदेश

प्रेस पर हमला

'माया' (३० सितंबर, '८७) में प्रकाशित 'पोल खोलने की सजा' यह सावित करता है कि राजीवजी ने बोफोर्स और पनडुब्बियों के सौदों में कमीशन खाया है। यही भारत की जनता जानने की इच्छुक थी। यदि गोयनका ने ३३.५ लाख की कर चोरी की है, तो इससे ज्यादा (१०० करोड़ रुपए की) तो रिलायंस समूह के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ने की है। गोयनकाजी के यहां छापा डालकर राजीवजी ने देश कों दिखा दिया है कि असलियत को जेनता के बीच लाने की सजा यह है। क्या राजीवजी की यह कार्यवाही प्रेस-समुदाय की कलम को रोक पायेगी? छापा अभियान द्वारा यदि राजीवजी देश को सचाई के रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो छापा उन मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सचिवों और सलाहकारों के यहां भी पड़ना चाहिए, जिनके पास कल तक डीजल के लिए पैसे तक नहीं थे और आज करोड़पति और अरबपति बन बैठे हैं। —शिवराज पटेल, चुरहट, म०प्र०

नींव में ही जातिवाद

'माया' के ३० सितंबर अंक की आवरण कथा 'ठाकुर बनाम ब्राह्मण' पढ़कर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्रारंभ से ही कांग्रेस देश से जातिवाद, वर्गवाद संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद की जोरशोर से भर्त्सना करती रही है, परंतु इस राष्ट्रीय दल का स्वरूप कैसा है, यह सर्वविदित है। अब यह दल ठाकुर-ब्राह्मण संघर्ष में उलझा है। अतीत में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और श्रीमती इंदिरा गांधी सभी ने इसके विरुद्ध बातें कीं, किंतु अपने सजातियों (ब्राह्मणों) को चुन-चुन कर नियुक्त किया। —चंद्रकांत यादव, चांदीतारा, वाराणसी

विकल्प की तलाश

विकल्प की तलाश में बदहवास विपक्ष (३० सितंबर) पढ़ा। विकल्प की तलाश में इधर-उधर हाथ-पैर मार रहा विपक्ष भविष्य में कितना सफल या असफल होगा, यह तो समय ही बतायेगा!

समझदार व्यक्ति वह है जो ठोकर खाने के बाद संभल जाये, किंतु विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि विपक्ष कभी यहां सशक्त नहीं रहा और विपक्षी अनगिनत ठोकरें खाने के बाद संभल नहीं रहे हैं! इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी दल सीख लेने के बजाय, अपने अहकार को ज्यादा महत्व दे कर ठोकर-पर-ठोकर खाने के आदी हो चुके हैं! —श्रीमती हेमलता उपाध्याय, घिनोदा (खांचरौद)

प्रेस की एकता

३० सितंबर, '८७ के अंक में 'इंडियन एक्सप्रेस पर छापा : पोल खोलने की सजा' पढ़ने को मिला। मानना होगा भारतीय पत्रकारिता को कि एकता है इसमें। यह चाहे गलत करे या सही, इनके विरुद्ध यदि कुछ भी हुआ, तो एक स्वर में स्वतंत्रता की दुहाई देने लगेगी। 'एक्सप्रेस-समुदाय' पर पड़े छापे ने देश व विदेश में हलचल तो मचायी ही, साथ ही पत्रकारिता जगत को भी लगा कि यह उनकी स्वतंत्रता पर हमला है। लेकिन क्या ऐसा ही है? शायद नहीं। अपराध चाहे प्रभावहीन गरीब व्यक्ति करे या प्रभावशाली व्यक्ति। अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, भारतीय संविधान में सभी को (गुनहगार) दण्ड देने का प्रावधान है। —मनोज कुमार द्विवेदी, अनूपपुर, शहडोल, म०प्र०

राजर्षि की उपाधि गलत

३० सितंबर की 'माया' पढ़ी। 'ठाकुर बनाम ब्राह्मण : शामत राजाओं की या राजीव की' लेख पढ़कर अत्यंत वेदना हुई। काशी विद्वतपरिषद द्वारा वी०पी० सिंह को जिस प्रकार राजर्षि की उपाधि दी गयी, वह तो गलत है ही, लेकिन 'माया' ने जिस तरह प्रकाशित किया है, उससे लगता है कि वह भी राजर्षि की उपाधि के दिये जाने को उचित मानती हैं। वी०पी० सिंह में राजर्षि जैसे कोई भी गुण नहीं हैं। यदि उनकी तथाकथित ईमानदारी, साहस और प्रगतिवादी विचारों को यथावत स्वीकार कर भी लिया जाये, तो भी वह

रेशमि बालोंका
जूँ, लिख और
खुशकी से
रक्षण किजिए।
अल्कोहोल रहित आयुर्वेदिक तेलयुक्त सुजानिल्स
लाइसिल
सुवासित
जूं नाशक
LiCEL
LICE KILLER
सुजानिल
केमो इंडस्ट्रिज
६९ वानवडी, कोंढ़वा रोड,
पुणे ४११ ०४०
EXPRESSO/87/HIND

चिट्ठियां

'राजर्षि' की उपाधि की कसौटी पर कहीं से भी खरे नहीं उतरते हैं। उस पर भी ऐसी परिस्थिति में आयोजित उपाधि समारोह, जिसमें विद्वत् परिषद के अध्यक्ष एवं शंकराचार्यों में से कोई भी उपस्थित नहीं हो और भी आलोचना तथा आपत्ति का विषय बन जाता है। —डी०एन० शर्मा, प्रेम नगर, बरेली

लड़ाई कुरसी की

'माया' के ३० सितंबर के अंक में विजय दत्त और रंजना कक्कड़ का लेख 'ठाकुर बनाम ब्राह्मण : शामत राजाओं की या राजीव की' पढ़ा। यह जानकर आश्चर्य एवं दुख हुआ कि 'माया' जैसी राष्ट्रस्तरीय पत्रिका ऐसे बचकाने लेख भी प्रकाशित कर सकती है, जो सचाई से कोसों दूर हों। असलियत यह है कि पार्टी के कुछ स्वार्थी तत्व एवं पद की लालसा रखने वाले लोग पूर्व राजा-महाराजा तथा ब्राह्मणों के बीच जातिवाद की दीवार खडी करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि कुछ रायों, त्रिपाठियों व मिश्रों के कारण समूचे ब्राह्मण समाज पर कीचड़ उछाल कर समाज को ही कलंकित करे। अगर सचाई पर नजर डाली जाये, तो यह न्याय और अन्याय के बीच संग्राम है। एक तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं उनके सहयोगी अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ राय, त्रिपाठी, मिश्र और दीक्षित बोफोर्स तोप, जर्मन पनडुब्बी सौदे में हुए भ्रष्टाचार तथा दलाली के आरोपों से केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बचाने में लगे हैं। ऐसे विवाद को किसी जाति, धर्म, सप्रदाय विशेष से जोड़ना जातिवाद को बढ़ावा देना है, जिसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। —राम नारायण भारद्वाज, सवाईमाधोपुर (राज०)

अब दिल्ली फतह करें

इस पत्र का संबंध 'विकास कलकत्ता का या काले धन का' (१५ सितंबर, '८७) से है। जब जयप्रकाश ने विचारों की दुनिया एवं समाज सुधार की दुनिया से हटकर भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाकर क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहा, तो ठीक विपरीत प्रकृति के लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जे०पी० ने 'जनेऊ तोड़ो अभियान' चलाकर जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का उपक्रम किया, तो जितने जातिवादी तत्व थे उनके साथ हो लिये। पूंजीवादियों ने लोकनायक-लोकनायक की रट लगाना शुरू कर दी। परिणामस्वरूप जे०पी० आंदोलन पूर्णतः विफल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान समाजवादी एवं साम्यवादी वास्तव में किसी दूसरे पथ के पथिक हैं, जो समाजवाद-साम्यवाद से सबसे ज्यादा घृणा करते हों, वहीं समाजवादी-साम्यवादी होने का दम भरते हों। —आशीश, कुमार चौधरी, दरभंगा, बिहार

बिहार किधर जा रहा है?

'माया' (३० सितंबर, '८७) में प्रकाशित है?' लेख पढ़ा। बिहार में बंदूक की नोक पर हरवाही का चित्र भी देखा। भारत में शायद बिहार ही एक ऐसा प्रांत है, जहां आजादी के ४० साल बाद भी ९७ प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिता रही है। आज बिहार में भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद लूट-खसोट, हरिजन-आदिवासी निर्धनों पर अत्याचार बढ़ रहा है। बिहार में इंसानी रिश्ता खतम होता जा रहा है। गौतम बुद्ध, दधीचि एवं अशोक का बिहार आज भ्रष्टाचार के बोझ से दबा जा रहा है। बिहार के नेताओं तथा समाज सुधारकों को इन समस्यांओं के समाधान के लिये कोई चिंता ही नहीं। —श्यामबिहारी लाल, एरिया ९ मैथन, पत्रा० मैथन, ज़िला धनबाद, बिहार

जनता की सेवा

१५ सितंबर का अंक पढ़ा। इस अंक में हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह और अरुण नेहरू को जनसमूह के बीच मुजफ्फरनगर में देखा। हमें तरस आता है कि ये खुदा के फरिश्ते, देवदूत कांग्रेस-इ से निष्कासित होने के पूर्व कहां थे? क्या निष्कासन के पूर्व किसान वर्ग पर परेशानी के बादल नहीं मंडराते थे या भारत में गरीबी नहीं थी। सब कुछ था, लेकिन तब इनका समय हाईकमान की जी-हजूरी में व्यतीत होता था। अब हाईकमान ने सेवा समाप्त (निष्कासित) कर दी, तो इनको गरीब जनता और शोषित किसान की याद आयी। याद भी क्यों नहीं आती, इन्हीं से तो कल्याण होना है। यदि कांग्रेस की चाटुकारिता करने को मिलती, तो अभी भी इनको जनता की याद नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस के प्रताप से पुनः राज्यसभा के सदस्य हो जाते। लेकिन अब तो इन्हें वोट लेना है, नहीं तो ये 'न राम के होंगे न रहीम के'। —जितेंद्र ओझा, पुत्र श्री गजेंद्र नाथ ओझा, १९३, तुलाराम बाग, इलाहाबाद

खयालात

मैं भारत को अपराधियों के लिए आदर्श जगह मानता हूं। **—चार्ल्स शोभराज 'जनसत्ता' में**

'जनतंत्र' बंबई और कलकत्ता के सेठों के हाथ नीलाम कर दिया गया है। **—वी०पी० सिंह 'नवभारत टाइम्स' में**

शंकराचार्य निरंजनदेव को मेरी चुनौती है कि वह अपनी गुफा गोवर्धन पीठ से निकलकर प्रबुद्ध जनों के बीच में दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर शास्त्रार्थ कर लें **—स्वामी अग्निवेश, 'नवभारत टाइम्स' में।**

यह हमारे लिये सबसे बड़ी क्षति है। रफी के बाद वह (किशोर कुमार) हमारे संगीत की आत्मा थे। **—संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 'जनसत्ता' में**

यदि वे (सिख उग्रवादी) चाहें तो कनाडा में खालिस्तान बना सकते हैं। भारत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। **—राजीव गांधी, खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर, वैंकुवर में**

हेगड़े

जिस शासक की आंखें छोटी हो जायें और कान बड़े, वह टिक नहीं सकता। **—चंद्रास्वामी 'दिनमान' में।**

भाजपा की मदद से सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ना सबसे बड़ा मजाक है।

—ई०एम०एस० नंबूदरीपाद

बेनजीर

सैद्धांतिक रूप से मैं ऐसा नहीं मानता कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में कोई बहुत बड़ा अंतर है।

—रामकृष्ण हेगड़े, 'सनडे आब्जरवर' में

जब आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते फिर भी ऐसा दिखावा करते हैं कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तब आप और कुछ नहीं सिर्फ सब ओर से दिक्कतों को दावत देते हैं।

—बेनजीर भुट्टो, पाक की परमाणु नीति पर

देवानंद

मैं अकसर अपनी रफ़्तार इसलिए धीमी कर देता हूं, जिससे दूसरे लोग मेरा साथ पकड़ सकें।

—देवानंद, 'फिल्मफेयर' में

मैं इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करती कि महिलाएं पुरुषों के नैतिक समर्थन के बिना भी जी सकती हैं। **—प्रसिद्ध गायिका शैरोन प्रभाकर**

हमारे परिवार ने रूपकंवर की पूजा करनी शुरू कर दी है। वह देवी का अवतार थी।

—मूलं सिंह, रूप कंवर का भाई

संघं शरणं गच्छामि !

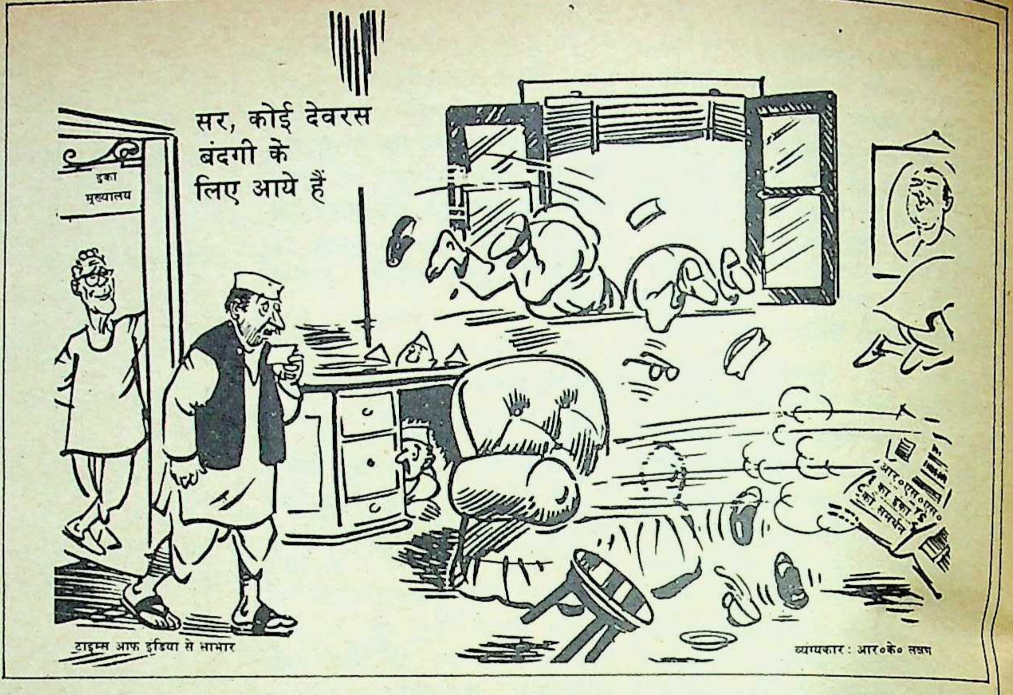
सर, कोई देवरस बंदगी के लिए आये हैं
इंका मुख्यालय
आर०एस०एस० का इंका को समर्थन

टाइम्स आफ इंडिया से साभार

व्यंग्यकार : आर०के० लक्ष्मण

गोपी अरोड़ा को जैसे ही मौका मिला, वह आंख बचाकर दिल्ली दरबार में लगी 'शाखा' से उड़न छू हो लिये। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें? वह भाग कर जैसे ही दिल्ली दरबार के 'कंट्रोल रूम' में घुसे, वहां सैम पेटरोडा खाकी निक्कर, सफेद कमीज, काली टोपी पहिने और हाथ में लाठी लिये 'कंट्रोल रूम' पर पहरा दे रहे थे। गोपी ने अपनी काली टोपी उतार कर फेंकी और चट से खाकी निक्कर उतारने के लिए बटन खोलने शुरू कर दिये। सैम से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी लाठी को भांजा। गोपी ने इतने में खाकी निक्कर के बटन छोड़कर तुरन्त काली टोपी पहन ली और लाठी की मार से बचने के लिए वह जोर से 'दक्ष:' कहकर सीधे खड़े हो गये। 'दक्ष:' सुनते ही सैम की लाठी नीचे आ गयी और वह भी सीधे तनकर खड़े हो गये। गोपी ने तने-तने फिर से चीख मारी 'ध्वज प्रणाम'। सैम ने और तनकर सीधे हाथ को अपनी छाती के समानांतर कर लिया। गोपी ने फिर आदेश दिया— 'प्रार्थना'। सैम शुरू हो गये— "नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदूभूमे..." सैम की आंखें प्रार्थना से विभोर होकर बंद हो गयीं, तो गोपी ने हाट लाइन पर गोर्बाचोव को ले लिया— "सर, सब गड़बड़ हो गया है। बाला साहब देवरस दिल्ली दरबार में घुस आये हैं। उनके आते ही सारा दरबार संघी हो गया है। सुबह-शाम नहीं, बल्कि चौबीसों घंटे यहां आर०एस०एस० की शाखा लग रही है।" मास्को ने पूछा, "अरे वह अपना के०एन० क्या कर रहा है?" गोपी अरोड़ा उसका कोई जवाब दें कि खाकी निक्कर पहने माखन लाल फोतेदार अपनी इस्पाती लाठी लिये कंट्रोल रूम आ धमके। पहले उन्होंने आंख बंद किये हुए सैम को 'प्रार्थना' करते हुए देखा, तो बहुत खुश हुए। लेकिन जब गोपी को गोर्बाचोव से बतियाते देखा, तो कोयले की जलती हुई खान हो गये। उन्होंने अपनी इस्पाती लाठी घुमाकर गोपी की पीठ पर दे मारी। गोपी के हाथ से टेलीफोन का चोंगा छूट गया— "एक विभीषण राजा मांडा से अभी पिंड नहीं छूटा। यह दिल्ली दरबार में तू दूसरा विभीषण पैदा हो गया।" फोतेदार ने एक दूसरी इस्पाती लाठी घुमाकर गोपी के सिर पर मारी। गोपी वहीं ढेर हो गये। सैम का ध्यान टूट गया। वह फोतेदार से कुछ पूछें कि उसके पहले एक इस्पाती लाठी सैम के ऊपर भी आ गयी "तुझको अमरीका इसीलिए लाये थे कि दिल्ली दरबार के कंट्रोल रूम को ठीक-ठाक रखे। तू हमेशा गोपी को मास्को से बात कराता रहता है।' सैम ने इस्पाती लाठी के वार से कराहते हुए कहा, "सर गलती हो गयी है।" सैम 'दक्ष:' की स्थिति में आ गये। फोतेदार ने कंट्रोल रूम पर इधर से उधर निगाह दौड़ायी और उसके बाद 'आरम' का आदेश देकर वहां से चलते बने।

कंट्रोल रूम में धमाचौकड़ी मचाकर फोतेदार दरबार के गलियारे में आये। उन्होंने अपनी इस्पाती लाठी बगल में दबायी और पाकेट से कैंची सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट सुलगा, खड़े... खड़े चार छह कश खींचे। तभी उन्होंने देखा, गलियारे की दूसरी ओर से खाकी निक्कर में जार्ज और सतीश शर्मा बतियाते चले आ रहे हैं। फोतेदार ने तुरन्त सिगरेट को जूते की टो के हवाले कर दिया। सतीश ने तो मुंह फेर लिया, लेकिन जार्ज ने सूंघते हुए फोतेदार से कहा, "यहां सिगरेट कौन पी रहा है?" फोतेदार ने तुरन्त जवाब दिया, "अरे और कौन, वही गोपी। खाकी निक्कर पहन ली है, लेकिन अभी भी गोर्बाचोव से नीचे बात नहीं कर रहा है।" जार्ज ने फोतेदार की बात का जवाब नहीं दिया और लपककर उनकी पाकेट से कैंची सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। उसके बाद दोनों आगे चलते बने। इतने में पीछे से जनानी आवाज़ आयी, "जार्ज जी, जार्ज जी।" जार्ज और सतीश दोनों ने पलटकर देखा तो खाकी निक्कर में नजमा हेपतुल्ला, हाथ में डंडा लिये भागी-भागी आ रही थीं। नज़मा को खाक़ी निक्कर में देखकर, जार्ज और सतीश तो बिलकुल सामान्य ही रहे, लेक़िन फोतेदार ने मक्खन लगाते हुए कहा, "अच्छा हुआ आपने निक्कर पहन ली। बड़ी स्मार्ट लग रही हैं।" नज़मा ने फोतेदार को मुंह बिचकाते हुए कहा, "रहने दीजिए, मैं आपसे बात नहीं करती। वह जार्ज की तरफ मुखातिब होकर बताने लगीं कि सारी इंकाई औरतें निक्कर पहन कर दरबार के लान में एकत्र हो गयी हैं। क्या हम लोगों की अलग से शाखा लगेगी या मरदों के साथ ही हम लोगों को खड़ा किया जायेगा। जार्ज ने नज़मा से कहा, "तुम जाकर उन्हीं औरतों के साथ खड़ी होओ। अभी इस विषय पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल की बैठक में बाला साहब देवरस से शास्त्रार्थ चल रहा है। देवरसजी ने प्रस्ताव रखा है कि सारे लोगों का पहले भारतीयकरण किया जाये।" नज़मा ने आश्चर्य से अपनी आंखें चश्मे के बाहर निकाल लीं, "क्या मतलब! भारतीयकरण। अरे हम लोग परदेसी थोड़े ही हैं जो भारतीयकरण की जरूरत पड़ रही है।" सतीश शर्मा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "नज़मा, भारतीयकरण से मतलब हिन्दूकरण से है।" जार्ज ने अपने गले में पड़े 'क्रास' को छिपाते हुए कहा, "क्या फर्क पड़ता है। पेट के लिए आदमी को क्या-क्या नहीं करना पड़ता है। हिन्दूकरण भी कर लेंगे।" नज़मा का चेहरा मुरझा गया। वह पीछे पलट लीं।

दिल्ली दरबार

नरेश चन्द्र चतुर्वेदी को जैसे ही खबर मिली कि देवरसजी खुलकर दिल्ली दरबार के साथ आ गये हैं, तो वह इंका मुख्यालय की जंजीरें तोड़कर दिल्ली दरबार में जा गिरे। साथ में ले गये दिल्ली दरबार के लिए एक खाकी निक्कर, एक सफेद कमीज, एक काली टोपी और एक लाठी। दिल्ली दरबार सोशलिस्ट लबादा पहने चहलकदमी कर रहे थे। जैसे ही गोपी अरोड़ा ने देखा कि नरेश चन्द्र चतुर्वेदी खाकी निक्कर पहने हुए दिल्ली दरबार में घुसे आ रहे हैं, उन्होंने ब्लैक कैट को 'सू' कर दिया। नरेश चन्द्र पर ब्लैक कैट जब तक चढ़ बैठे कि उसके पीछे प्रोफेसर जे०एन० रंगा, पशुपति नाथ सुकूल, श्रीपति मिश्र आदि-अनादि खाकी निक्कर पहने हुए, लाठी भांजते हुए दिल्ली दरबार में घुस आये। ब्लैक कैट आदि-अनादि पर भी लपके, तो मौका पाकर नरेश चन्द्र चतुर्वेदी दरबार के करीब हो लिये। चतुर्वेदी ने 'संघी नमस्ते' करते हुए दिल्ली दरबार को खाकी निक्कर, सफेद कमीज, काली टोपी, लाठी तथा एक संघी कोष पकड़ाते हुए कहा, श्रीमान जी, हमारे सारे संकट दूर हो गये हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारी सेवा में आ गयी है। अब देखूंगा कि राजा मांडा कैसे बचता है? आर०एस०एस० उसे ठिकाने लगा देगा।" दिल्ली दरबार ने मुस्कराते हुए कहा— "हे कनपुरिये अढ़ैती, हम इस संघी वस्त्रों और शब्द कोष को कैसे धारण कर सकते हैं। मैं तो सोशलिस्ट लबादा धारण किये हुए हूं।" नरेश चन्द्र संस्कृत में हिंदी भाष्य के साथ शुरू हो गये, "हे महामानव, युग पुरुष दिल्ली दरबार! आप समाजवादी वस्त्रों के ऊपर संघी वस्त्र पहनकर इस देश की मूर्ख जनता को दिग्भ्रमित कर दीजिए, यह सिद्ध करने के लिए कि आप मौका आने पर हर तरह के वस्त्रों और विचारों को सहजता से धारण कर सकते हैं। अभी आपको अगले कुछ ही दिनों में विश्व मानव रीगन से मिलने जाना है। आपको खाकी निक्कर में देखकर वह बहुत प्रसन्न होंगे।"

दिल्ली दरबार के ज्ञान-चक्षु खुलने लगे। उनको लगा कि पूरा देश खाकी निक्कर पहने कवायद कर रहा है। जगह-जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं— "नमस्ते सदा वत्सले, मातृभूमे..." तभी सहसा दिल्ली दरबार के मुंह से निकला— 'उपवेश'। सामने खड़े नरेश चन्द्र चतुर्वेदी धड़ाम से पल्थी मारकर संघी कोष से फिर एक शब्द 'उत्तिष्ठः' उच्चारित किया, तो नरेश चन्द्र चतुर्वेदी खटाक से उठकर खड़े हो गये। 'दक्षः' के बाद नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 'आरम' में आये, तो दिल्ली दरबार का हाथ उनके कंधे पर शाबाशी के लिए चला गया— "अरे कनपुरिये नरेश, ये तो कमाल के शब्द हैं। अगर मैं खाकी निक्कर पहन कर इन शब्दों को उच्चारित करूंगा, तो सारा देश मेरा हुकुम मानेगा।" दिल्ली दरबार के और करीब होते हुए नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने कहा, "दिल्ली जी, दरबार जी महाशय, सोशलिस्ट लबादे को उतार फेंके और तुरन्त खाकी निक्कर धारण कर लें।" दिल्ली दरबार ने नरेश के हाथ से खाकी निक्कर, सफेद कमीज, काली टोपी तथा लाठी ग्रहण कर ली। उसके बाद दिल्ली दरबार ने ऐलान किया, "अब हमारे दरबार से सारे छोटे-बड़े सेवक संघी मेकअप करके दिन रात खाकी निक्कर पहनेंगे।" नरेश चन्द्र चतुर्वेदी खुशी से बिन पिये झूम उठे और भागे-भागे इंका मुख्यालय पहुंचे और खबरचियों के बीच ऐलान कर दिया— "बाला साहब देवरस जी ने दिल्ली दरबार को समर्थन देने की जो उद्घोषणा की है, उसका स्वागत है।" दिल्ली दरबार के पार्टी भोंपू गुलाम नबी आजाद को जब पता चला कि कनपुरिये नरेश ने खाकी निक्कर पहन ली और साथ में दरबार को भी खाकी निक्कर पहना दी है, तो आपे से बाहर हो गये। वह सीधे केदार नाथ सिंह के कमरे में जा धमके— "के०एन० खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा मौका-मुआयना करूंगा।" के०एन० पार्टी भोंपू की धमकी में आकर कुरसी के ऊपर खड़े हो गये। गुलाम नबी ने 'संघी पकड़ डिटेक्टर' के०एन० के ऊपर से नीचे घुमाया तो वह चूं...चूं की आवाज करने लगा "यह क्या तुम भी धोती के अंदर खाकी निक्कर पहने हुए हो। तुम तो कहा करते हो मेरी संघियों से पैदायशी दुश्मनी है।" के०एन० कुरसी से धड़ाम से कूदे— "आजाद भाई। मैंने वामपंथी मुखौटा दिल्ली दरबार को मूर्ख बनाने के लिए पहन रखा है। अगर मेरा संघी दिल न होता, तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों आता?" इसी बीच केसरीजी आ धमके। गुलाम नबी केसरीजी की तरफ मुखातिब होते ही सन्नाटे में आ गये। केसरीजी की धोती के अंदर से खाकी निक्कर झांक रही थी। केसरीजी ने गुलाम नबी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, "अरे गुलाम, तू किस फेर में फंस गया है। हमाम में सब नंगे हैं। तू भी तो लीगी टोपी पहने कश्मीर की वादियों में सालों घूमा है। इस पचड़े में क्यों पड़ रहा है? वह अपना यूथ कांग्रेसिया आनंद शर्मा तो अभी तक गाहे-बगाहे खुल्लम-खुल्ला खाकी निक्कर पहने घूमता है। उसको तो अब जप ही लिया जाये, तो अच्छा है।" केसरीजी आगे कुछ और बोलें कि के०एन० ने मेज पर से मक्खियों से घिरे रसगुल्ले को हाथ में लेकर केसरीजी की बोलती बंद कर दी— "केसरीजी, अन्दर से हम लोग लीगी, संघी और हिन्दू महासभाई जो भी हों, लेकिन ऊपर से नहीं दिखना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है। नरेश चन्द्र चतुर्वेदी की खाकी निक्कर तो हमें उतरवानी ही पड़ेगी, नहीं तो वी०पी० सिंह हमको नहीं छोड़ेगा।" रसगुल्ले को निगलते हुए केसरीजी गहन चिन्ता में डूबने लगे— "के०एन० तुम्हारी बात पर गौर करना जरूरी है। चलो दिल्ली दरबार चलें।"

> ***"रीगन के कहने पर तुमने श्रीलंका में अपनी गर्दन दे दी। हम इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब तुमने बाला साहब देवरस को दिल्ली दरबार में घुसेड़ लिया है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अंदर से संघी बने रहो, लेकिन अपने चेहरों पर वामपंथी मुखौटा लगाये रखो।" दिल्ली दरबार अपनी सफायी दें कि उसके पहले ही गोर्बाचोव ने मास्को में टेलीफोन का रिसीवर रख दिया।***

दिल्ली दरबार में हर तरफ भगवा लहरा रहा था। दिल्ली दरबार खाकी निक्कर में कार्यवाह बने शाखा के सामने खड़े थे। नरेश चन्द्र, चतुर्वेदी मुख्य प्रचारक 'दक्षः' और 'आरम' किये जा रहे थे। प्रार्थना— 'नमस्ते सदा वत्सले...' हो चुकी थी। मारग्रेट अल्वा गण प्रमुखणी बनी 'खो-खो' खिला रही थीं। दिल्ली दरबार भी खो-खो खेलने लगा। केसरीजी ने चट से अपनी धोती खोल दी और खाकी निक्कर में आ गये। केदार नाथ सिंह, मूपनार, गुलाम नबी सभी खाकी निक्कर में आकर शाखा में शामिल हो गये। जमकर शाखा लगी और फिर कुछ देर के लिए जब विसर्जित हुई, तो गोपी अरोड़ा के इशारे पर इन सबने दिल्ली दरबार को घेर लिया। गोपी ने तुरन्त दिल्ली दरबार को गोर्बाचोव का टेलीफोन पकड़वा दिया। टेलीफोन के चोंगे में रूसी का हिन्दी अनुवाद आ रहा था— "रीगन के कहने पर तुमने श्रीलंका में अपनी गर्दन दे दी। हम इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब तुमने बाला साहब देवरस को दिल्ली दरबार में घुसेड़ लिया है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अंदर से संघी रहो, लेकिन अपने चेहरों पर वामपथी मुखौटा लगाये रखो।" दिल्ली दरबार अपनी सफायी दें कि उसके पहले ही गोर्बाचोव ने मास्को में टेलीफोन का रिसीवर रख दिया।

मास्को के टेलीफोन के बाद दिल्ली दरबार विचलित हो उठे। केसरीजी आगे बढ़े— "सर, हम सबको खाकी निक्कर के ऊपर फिर से खादी का कुरता-पैजामा पहन लेना चाहिए।" के०एन० सिंह ने तड़ाक से बयान जारी किया— "दिल्ली दरबार को बाला साहब देवरस की आर०एस०एस० का प्रमाणपत्र या सहयोग नहीं चाहिए।"

—दरबारी लाल

वीर बहादुर का गधा

"हुजूर, मैं तो आपका गधा हूं, जितना चाहे बोझ लाद दीजिए, लेकिन कम न दीजिए। हल्का बोझ लेकर चलने में मजा नहीं आता है।" उत्तर प्रदेश के वजीरेआला जनाब वीर बहादुर सिंह के सामने इस तरह की फरियाद उनके ही एक नायब वजीर चेतराम गंगवार ने की। गंगवार के मासूम चेहरे को देखकर वीर बहादुर पहले मुस्कुराये फिर ठहाका लगाकर बोले, "तुम जैसे बहुत से हैं मेरे पास। सब पर बोझ लादना है।"

यह वाकेआ है, ३ अक्टूबर की शाम ७ बजे का। स्थान था मुख्यमंत्री का पांचवी मंजिलवाला कार्यालय। दो दिन पूर्व ही वीर बहादुर ने अपनी मंत्रिपरिषद के पांच सदस्यों के विभागों में थोड़ा फेरबदल किया था। इनमें तीन राज्यमंत्री रामऔतार दीक्षित, भोलाशंकर मौर्य और सीताराम निषाद को थोड़ा और वजनी किया गया था। चेतराम गंगवार को इस बात का काफी मलाल था कि वीर बहादुर ने रामऔतार दीक्षित को ग्राम्य विकास विभाग का अतिरिक्त भार क्यों दे दिया, जबकि गंगवार इस विभाग के राज्य मंत्री थे। आखिर एक ही विभाग के लिए दो-दो राज्य मंत्री क्यों?

उसी दिन यानी तीन अक्टूबर को जब वीर बहादुर ने दो राज्यमंत्रियों राम नाथ मुंशी और कुमारी सरस्वती अम्माल को भी वजनी बना दिया, तो गंगवार गुस्से से लाल-पीले हो उठे। उन्होंने फौरन अपना इस्तीफा टाइप कराया और उसे लेकर वीर बहादुर के सामने जा पहुंचे। आव देखा न ताव, वह कई लोगों के सामने ही बोल पड़े, "मैं गांव का जाहिल आदमी हूं, लेकिन ६ टर्म से एम०एल०ए० हूं। जिसे जुमा-जुमा चार दिन एम०एल०ए० बने हुआ, वह आज महत्वपूर्ण मंत्री बना हुआ है। आप पांच मिनट मेरी बात सुन लीजिए।"

वीर बहादुर को लगा कि गंगवार शायद उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। यही सोचकर वह डपट पड़े, "बड़े बेवकूफ हो, जो मन में आता है, बकते रहते हो।"

"हां, मैं तो जाहिल हूं, बेवकूफ हूं। इसीलिए इस पौने दो साल में आपने मुझे पौने दो मिनट का समय भी बात करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, यह चिट्ठी रखी है। जब समय मिले पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने अपना इस्तीफा लिख दिया है।"

यह सुनते ही सब दंग रह गये। वीर बहादुर भी थोड़ा अचंभे में पड़ गये। सब लोगों को कमरे से बाहर कर उन्होंने गंगवार से बात की। समझाया-बुझाया। थोड़ी देर बाद बुनकरों का एक प्रतिनिधि मंडल वीर बहादुर से मिलने आया।

बुनकरों की समस्याओं पर बातचीत के दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हथकरघा राज्यमंत्री निसार अहमद अंसारी को हटा दीजिए या उनका विभाग किसी दूसरे को दे दीजिए। गंगवार वहीं खड़े थे। वीर बहादुर नें उनकी ओर इशारा कर पूछा, "इन्हें यह विभाग दे दूं, ठीक रहेगा," सब एक साथ बोल उठे, "बिलकुल ठीक रहेगा।"

गंगवार ने मौका ताड़ा, "मैं हिन्दू अंसारी हूं। धर्म से हिन्दू हूं काम से मुसलमान। मुझे दे दीजिए यह विभाग, सबको ठीक कर दूंगा। मैं तो आपका गधा हूं बोझ लाद दीजिए, कम न कीजिए।"

निर्वाचन आयोग की धमकी

इलाहाबाद की लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर उ०प्र० सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच काफी तू तू-मैं मैं हो रही है। यह सीट सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के कारण खाली हो गयी है। पिछले दिनों नागालैंड के चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग इलाहाबाद में भी चुनाव कराना चाहता था। लेकिन उ०प्र० सरकार ने एक पत्र भेजकर निर्वाचन आयोग को सूचित किया कि राज्य में इस समय जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए प्रदेश सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि इलाहाबाद में चुनाव का प्रबंध करा सके। निर्वाचन आयोग ने इलाहाबाद में चुनाव नागालैंड के साथ चुनाव कराने की अपनी घोषणा को तो रोक दिया, लेकिन वह उ०प्र० सरकार के इस तर्क से कतई सहमत नहीं हुई। निर्वाचन आयोग ने तुरन्त उ०प्र० सरकार को लिखा, "सूखा केवल उ०प्र० में ही नहीं है, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी है। ऐसी स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया को कतई नहीं रोका जा सकता है।"

उ०प्र० सरकार ने निर्वाचन आयोग को फिर लिखा है, "इलाहाबाद बहुत बुरी तरह से सूखे से प्रभावित है। पूरी सरकारी मशीनरी सूखा राहत कार्य में लगी हुई है, इसलिए वहां चुनाव कराना सम्भव नहीं है।"

इस जवाब को भी निर्वाचन आयोग ने स्वीकार नहीं किया है। आयोग ने राज्य सरकार को धमकी दी है कि अगर अब कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो निर्वाचन आयोग अपना कोई प्रेषक भेजकर इलाहाबाद की स्थिति का अध्ययन करायेगी। उ०प्र० सरकार इससे काफी परेशानी में पड़ गयी है।

वस्तुस्थिति यह है कि उ०प्र० के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया है कि पूर्व रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का इलाहाबाद में बहुत प्रभाव है। उसी जिले के एक अन्य सांसद राम पूजन पटेल को जनमोर्चा के प्रदेशीय संयोजक बना दिये जाने के कारण इलाहाबाद लोकसभा की सीट कांग्रेस के लिए जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसी आधार पर राजीव गांधी ने यह फैसला कर रखा है कि फिलहाल किसी भी लोकसभा सीट का कोई चुनाव न कराया जाये। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या निर्वाचन आयोग इस पर चुप होकर बैठ जायेगा। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता का कहना है; "अगर उ०प्र० सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर निर्धारित समय के अंदर नहीं मिलता है तो आयोग को एक तरफा ही फैसला, इलाहाबाद की खाली लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के लिए लेना पड़ेगा।"

पिछले दिनों कुछ सांसदों ने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का ध्यान निर्वाचन आयोग की धमकी की ओर दिलाया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हम 'सिंह' हैं, 'गीदड़ धमकी' से डरने वाले नहीं। जब हम चाहेंगे तब इलाहाबाद में चुनाव होगा।

सोनिया की गोपनीय यात्रा

प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस बार अपने १२ दिनों के विदेश दौरे में अपनी पत्नी सोनिया गांधी को साथ नहीं ले गये। वैसे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर विदाई देने के लिए जो सरकारी निमंत्रण-पत्र शुरु में विशिष्टजनों को दिया गया था, उसमें यह लिखा हुआ था कि श्रीमती सोनिया गांधी भी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री के साथ जा रही हैं। लेकिन अंतिम समय पर जो निमंत्रण-पत्र दिया गया, उसमें सोनिया गांधी का नाम नहीं था। इसी से पता चला कि सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। राजीव गांधी के वैंकुवर में राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के बाद इकाई सांसदों और मंत्रियों के बीच यह चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर सोनिया गांधी विदेश-दौरे पर क्यों नहीं गयीं?

जानकार सूत्रों का कहना है कि राजीव गांधी के विदेश रवाना होने के बाद दूसरे दिन रात में वह कहीं विदेश रवाना हो गयीं। इसकी आधिकारिक सूचना किसी को नहीं दी गयी। ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी रोम चली गयीं। लेकिन प्रश्न यह है कि उनकी इस यात्रा को इतना गोपनीय क्यों रखा गया? क्या सुरक्षा के कारण ऐसा किया गया या फिर उनकी यह कोई गोपनीय यात्रा थी!

शोख, चंचल आवाज और मजाकिया अभिनय के जरिए ५८ वर्ष तक की उम्र में दर्शकों को हंसा और रुला देने वाले गायक किशोर कुमार १३ अक्तूबर, १९८७ को इस दुनिया को सदा-सदा के लिए अलविदा कह गये। लगभग तीन दशकों तक लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली आवाज अब नये गीत नहीं सुनायेगी। अभिनय (फिल्म-छमछमाछम) से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले किशोर कुमार गायन की हर शैली में माहिर थे। जहां अटपटे गीतों से वह सुननेवालों को गुदगुदा देते थे, वहीं दर्द भरे नग्मों से रुलाने की ताकत भी रखते थे।

किशोर कुमार और पुरस्कार एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गये थे। उन्हें आठ बार फिल्मफेयर पुरस्कार (चार बार लगातार) से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लासएंजिलेस में ई०एम०ई० पुरस्कार, १४ बार लायंस क्लब बंबई का पुरस्कार, एक बार लायंस क्लब दिल्ली का पुरस्कार, ७ बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन पुरस्कार और एक बार मध्यप्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार भी उन्हें मिला।

किशोर कुमार की अंतिम इच्छा थी कि गृह नगर खंडवा के अपने फार्म हाउस में खेती-किसानी करें। उनकी यह इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर उनके गृह नगर में उनका अंतिम संस्कार अवश्य हुआ। यानी किशोर कुमार जिस मिट्टी में पले बढ़े, उसी मिट्टी के आगोश में सदा-सदा के लिए सो गये। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कला की सेवा करते-करते ही वह अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे।

छाया: डी०आर० यादव

छाया: डी०आर० यादव

यह अदा है किशोर कुमार की। किशोर जब ऊब जाते, तो चुपके से मकान की छत पर हारमोनियम लेकर पहुंच जाते और वहां मनचाहे गीत गाते।

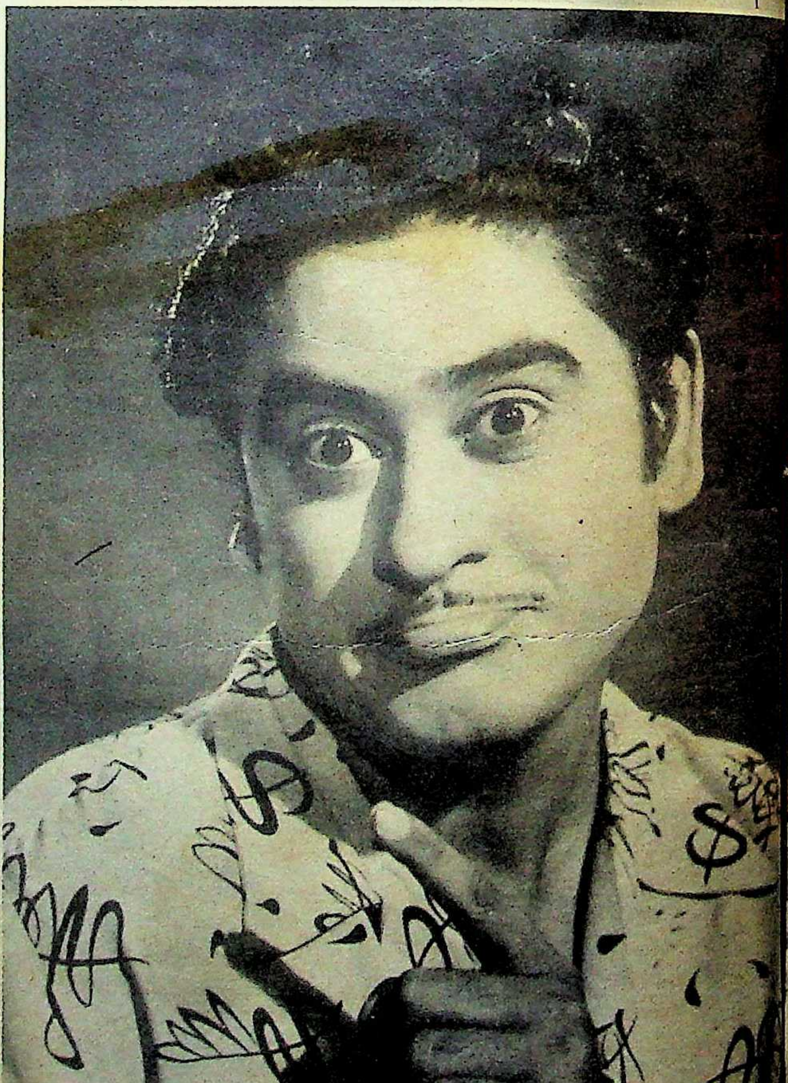

फिल्म 'शरारत' के एक हास्य दृश्य में किशोर कुमार। उनके साथ हैं, मीनाकुमारी और राजकुमार (ऊपर)।

'न्यू देलही' फिल्म में रोमांटिक अंदाज में किशोर कुमार और वैजयंती माला (नीचे)

'न्यू देलही' के एक अन्य दृश्य में किशोर कुमार (दायें)

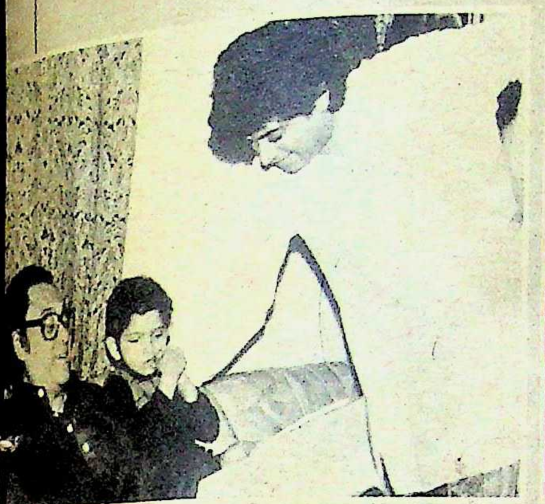

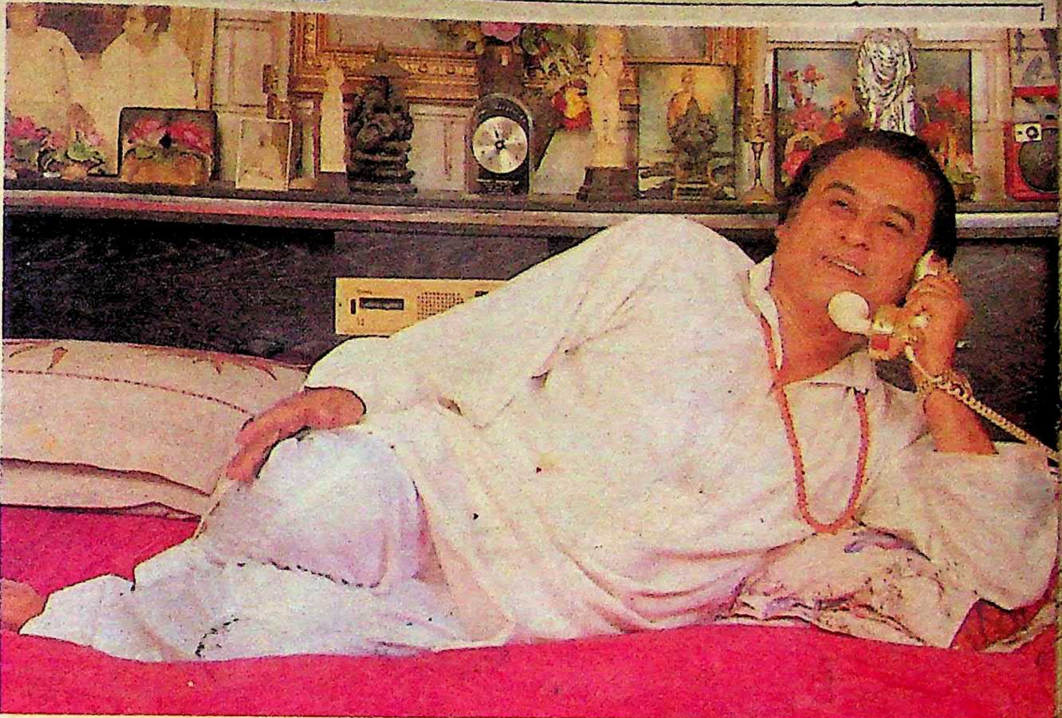

छाया: डी०आर० यादव

किशोर कुमार अपने दोनों बेटों-अमित और सुमित के साथ। (पहले कालम में ऊपर)

अध्ययन और ख्यालों में किशोर कुमार। (पहले कालम में बीच में)

लजीज खाने के शौकीन किशोर कुमार। (पहले कालम में नीचे)

शयनकक्ष में मां का चित्र। किशोर कुमार पर मां का बहुत प्रभाव था, इसीलिए अपने बंगले का नाम भी उन्होंने अपनी मां के नाम पर 'गौरी कुंज' रखा। (दूसरे कालम में ऊपर)।

कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे, दोनों जगह किशोर कुमार का कोई सानी नहीं था। (दूसरे कालम में बीच में)।

किशोर कुमार और अभिनेत्री श्यामा। (दूसरे कालम में नीचे)।

७०० करोड़ राम नाम से समाहित राम भक्त हनुमान की विश्व की सबसे विशालतम मूर्ति का अभिषेक १ जून, १९८७ को हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल शुकताल में बजरंग बली की यह विशाल मूर्ति प्रतिस्थापित हुई है।

गंगा नदी के तट पर ६४.७ फुट ऊंचे कद वाली इस हनुमंत मूर्ति के चरण ९ फुट तथा हथेली की लम्बाई ८ फुट है। जमीन से इसकी कुल ऊंचाई ७६.८ फुट है। आधार के लिए मूर्ति में पैरों से लेकर कंधे तक एक इंच मोटी १८ छड़ों से युक्त ३x४ फुट व्यास के दो स्तंभ हैं। यह गगनचुम्बी-सी दीखने वाली मूर्ति (सरिया, रोड़ी, सीमेंट) की बनी हुई है। एक विशेष बात यह भी है कि इस विशालतम मूर्ति को एक साधारण मूर्तिकार ने मात्र १०० दिन में निर्मित कर मूर्ति कला में एक नया कीर्तिमान कायम किया है।

यों तो मारीशस में स्थित ७२ फुट की नटराज की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची मानी जाती थी। किन्तु बजरंग बली की यह मूर्ति अपनी विशेषता के लिए अद्वितीय है।

दूसरे, पूरी मूर्ति राममय है। इस विशाल मूर्ति के निर्माण की योजना का संकल्प बिहार प्रांत के चाकुलिया नामक स्थान के निवासी प्रभुदयाल झुनझुनवाला ने किया था। इस विशाल मूर्ति के शिल्पकार हैं शहडोल (मध्य प्रदेश) निवासी केशवराम।

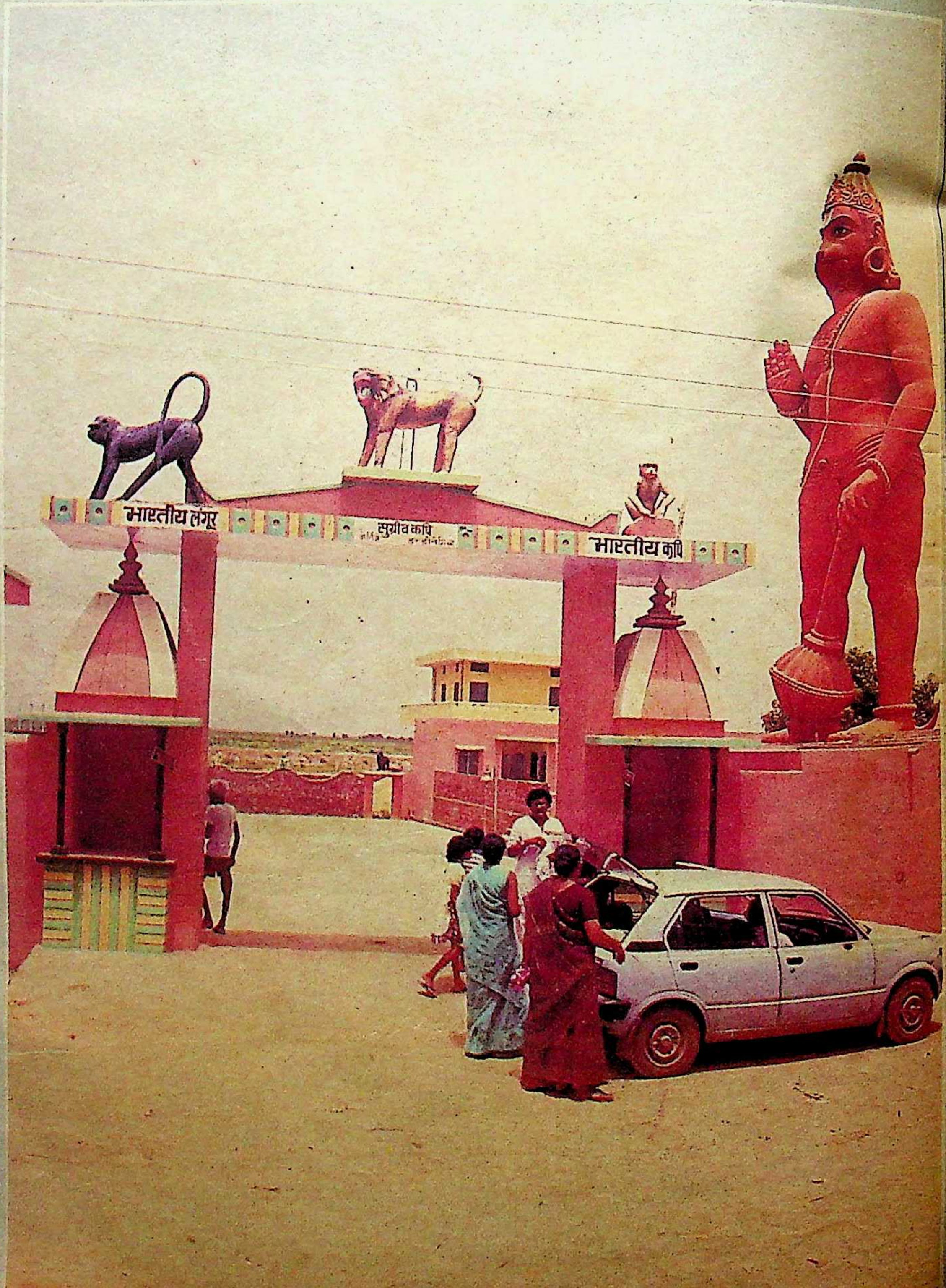

छाया : मनमोहन शर्मा

सावधान, ब्रह्मास्त्र बन रहा है!

'न मारा, न खून बहा, लाखों के सिर काट लिये'—इस पहेली का उत्तर है—रूस का नया हथियार—मानवघाती रेडियो फ्रीक्वेंसी हथियार। यह हथियार न तो वायुमंडल को प्रदूषित करेगा, न ही यह किसी शहर को ध्वस्त। इससे विकिरण और रेडियोधर्मिता भी नहीं फैलेगी—बस अदृश्य विद्युत तरंगें उठेंगी जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देंगी और पलक झपकते ही लाखों-लाख लोग बिना यह जाने-समझे ही मर जायेंगे कि उन्हें किसने किस हथियार से मारा। रूस ने यह हथियार करीब-करीब बना लिया है और दो-तीन सालों में ही वह इसका उत्पादन करने लगेगा। पश्चिमी देशों में इस नये हथियार से खलबली मची हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी लिंडन ला रोश ने तो इस हथियार को अपना चुनावी मुद्दा ही बना लिया है।

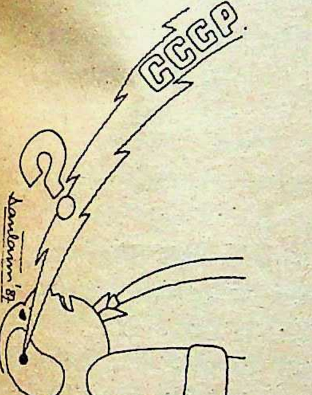

अंतरिक्ष युद्ध कार्यक्रम के पूर्व मनुष्य ने लड़ाई के तलवार, बंदूक, तोप, बम और प्रक्षेपास्त्र आदि जो भी हथियार विकसित किये, वे यांत्रिक क्रिया पर निर्भर थे। फिर आये रश्मि हथियार (बीम वेपंस), उसके बाद अमरीका ने बनाया न्यूट्रान बम—इससे संपत्ति का नुकसान नहीं होता, मानव संहार होता है और बम प्रभावित इलाके में जो विकिरण फैलता है, उससे यह क्षेत्र लोगों के रहने काबिल नहीं रह जाता। लेकिन रूस के इस नये हथियार में ऐसा कोई खतरा नहीं है और इसका मूल वैज्ञानिक सिद्धांत भी बहुत साधारण है।

मनुष्य का शरीर विभिन्न जीवित कोशिकाओं से बना है, अणु के मृत द्रव्य और जीवित कोशिका में फर्क सिर्फ इतना रहता है कि जीवित कोशिका में एक विशेष 'एकक तत्व' होता है जो अन्य कोशिकाओं से एक कमजोर विद्युत चुंबकीय समूह से जुड़ा होता है। यदि इस विद्युत चुंबकीय समूह में नियोजित तरीके से विद्युत चुंबकीय कंपन पैदा किया जाये, तो कोशिका की प्रक्रिया बिगड़ जायेगी और वह मर जायेगी। संचार, नौवहन राडार आदि संचार माध्यमों के लिए जो रेडियो तरंग पैदा की जाती है, उसका मनुष्य की कोशिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन रूस का यह नया हथियार सुगठित स्पंदन पैदा करता है, जिसमें भिन्न आवृत्तियां (फ्रीक्वेंसीज) एक साथ उत्पन्न होती हैं, जिनका प्रमुख निशाना मस्तिष्क की कोशिकाएं बनती हैं। सोवियत रूस बहुत दूर से दुश्मन के क्षेत्र में ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ता जायेगा और दुश्मनों की लाशें बिछती चली जायेंगी। देखना है, अमरीका इस हथियार के जवाब में कैसा हथियार बनाता है।

रावण का 'सत्याग्रह'

दशहरे की गहमागहमी के बीच पूरे देश में रामलीलाओं का ज्वार आ जाता है, जगह-जगह राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण और कुंभकर्ण आदि रामायण के पात्र पैदा हो जाते हैं, स्थान-स्थान पर कई दिनों तक रामलीलाएं होती हैं, कहीं भव्य तो कहीं नौटंकीनुमा, लेकिन दशहरे के दिन एक घटना हर जगह निर्विवाद रूप से होती है—वह है, रावण-वध। लेकिन हापुड़ के समीप एक कस्बे में हो रही रामलीला में दशहरे के दिन रावण ने मरने से इनकार कर दिया। राम बार-बार बाण चलाते थे, रावण मंच पर बस तलवार घुमाता जाता था। जब बहुत देर तक रावण नहीं मरा, तो राम बने पात्र ने पहले धीरे से कहा कि 'मरता क्यों नहीं?' लेकिन जब इसका असर नहीं हुआ, तो यही बात राम ने थोड़ा जोर से कही, इसके जवाब में रावण बने पात्र ने भी तलवार घुमाते हुए जोर से कहा, "मैं नहीं मरूंगा।"

राम-रावण युद्ध देख रहे हजारों दर्शकों के लिए यह नया मनोरंजन था। राम बाण-पर-बाण चलाये जा रहे थे, रावण उछल-उछल कर तलवार घुमा रहा था, उसके तेवर बतला रहे थे कि वह मरने के लिए तैयार नहीं है। मंच पर राम-रावण युद्ध जारी था, दर्शक भी अब रावण से मरने का अनुरोध करने लगे थे, लेकिन रावण 'न मरने' की अपनी जिद्द पर अड़ा था। रावण नहीं मरेगा तो रामलीला कैसे ख़तम होगी? रामलीला मंडली का मालिक भी परेशान था। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने पूछताछ की, तो पता चला कि रावण बने पात्र को नाटक मंडली के मालिक ने बकाया पारिश्रमिक नहीं दिया है इसलिए उसने मरने से इनकार कर दिया है। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप से रावण ने अपना बकाया पारिश्रमिक दो सौ रुपए प्राप्त किया, तब कहीं जाकर वह मरने के लिए तैयार हुआ।

मरहम का 'कवच'

अंध विश्वास किसी एक देश या कौम की धरोहर नहीं है। विकसित-से-विकसित देश में भी पूजा-पाठ किये बिना किसी वैज्ञानिक योजना तक का शुभारंभ नहीं किया जाता। दूसरे लोक में उसी पति को प्राप्त करने के लिए स्त्री जिंदा जल जाती है, तो अच्छी खेती, संतान प्राप्ति और किसी अनुष्ठान की पूर्ति के लिए बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन अफ्रीका के उगांडा देश में अंधविश्वास ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि दो सौ लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे।

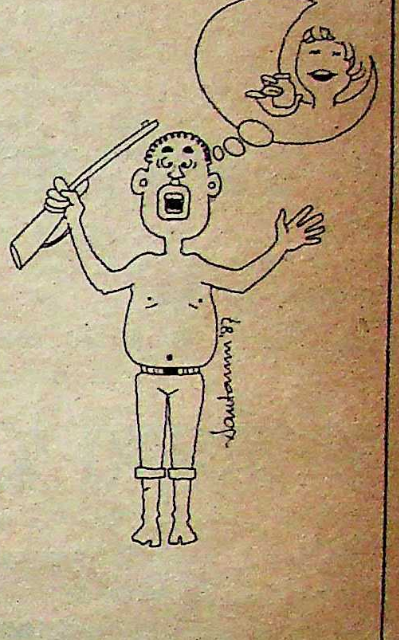

उगांडा सरकार का तख्ता पलटने के लिए वहां एक गुट छापामार लड़ाई लड़ रहा है। उसे 'होली स्पिरिट' नामक धार्मिक आंदोलन चलानेवाली एक खूबसूरत युवा महिला पुजारिन एलिस लाक वेना का वरदहस्त प्राप्त है। उसने विद्रोही छापामारों को एक खास तरह का मरहम बनाकर दिया और यह विश्वास दिला दिया कि इसे शरीर पर लगा लेने से गोली-बमों का शरीर पर कोई असर नहीं होगा। छापामारों को उस पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने शरीर पर वह मरहम लगाया। बिना कमीज पहने, पैंट को जांघ तक चढ़ाकर उन्होंने उगांडा सेना पर हमला बोल दिया। राजधानी कंपाला से २०० किलोमीटर दूर कायिती में यह लड़ाई हुई। मगर मरहम गोलियों को नहीं रोक सका और २०० छापामारों ने अपने प्राण गंवा दिये।

—संयोजन : विनोद मिश्र

रामधन

न हमारी कोई पार्टी है, न घोषणा पत्र

पहली नजर और पहला असर अकसर धोखा दे जाती है, यह बात नवगठित जनमोर्चा के संयोजक रामधन पर खरी उतरती है। उनके सौम्य, मृदुभाषी, विनीत, स्वप्नदर्शी व्यक्तित्व के पीछे एक व्यावहारिक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की स्पष्ट झलक है। जब वह श्रीमती गांधी की सत्ता के प्रारंभिक दिनों में चार बहुचर्चित जुझारू युवा तुर्कों में से एक थे, तब भी उनका यही तेवर था। तब एक क्रुद्ध युवा के रूप में उनमें मूलगामी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने और दलितों, पीड़ितों, वंचितों की वकालत करने की बेहद बेचैनी और जोश-खरोश था। उनकी कठोरता-सुदृढ़ता को उनके समर्थक जहां 'सिद्धांतनिष्ठ' करार देकर उनके पक्ष व पार्टियां बदलने का अर्थ समझाते हैं, वहीं कांग्रेसी नेताओं की मौजूदा जमात उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहती हैं। पर कौन क्या कहता है इसकी उन्हें परवाह नहीं है।

'जनमोर्चा' जैसे नये और लचीले आंदोलन ने मानो उन्हें अपनी विचारधारा पर अमल करने का सही अवसर प्रदान किया हो, जिसमें समाजवाद और आमूल परिवर्तनवाद का मिश्रण है। इसी की झलक उनमें भी मिलती है। इस मामले में वह वी०पी० सिंह से एकदम भिन्न हैं जो अपने क्रांतिकारी आह्वान के बावजूद परंपरावादी जैसे लगते हैं। जनमोर्चा के गठन के तुरंत बाद रामधन से विजय दत्त व रंजना कक्कड़ ने उनके राजेन्द्र प्रसाद रोड स्थित एम०पी० आवास के ड्राइंगरूम में भेंट की, जहां बदरंग नीली कालीन पर गेंदे की पंखुड़ियां चमक रही थीं और उसे एक विशेष स्वरूप प्रदान कर रही थीं। ठीक वैसे ही जैसे वह भारतीय राजनीति को अपने 'जनमोर्चा' से प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत हैं, उनसे बातचीत के अंश :

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

माया : जनमोर्चा के बारे में अ०भा० कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के बयानों के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

रामधन : नवल किशोर शर्मा, भगवत झा आजाद, ए०के० एंथोनी, रघुनंदन लाल भाटिया, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ये सारे के सारे पुराने व अनुभवी नेता लोग थे। उनका अपना स्तर था। किन विषयों पर क्या बात करनी है और कैसे करनी है, उन्हें मालूम था। आज जो नये पदाधिकारी हैं, उनके जो बयान छप रहे हैं, जनता स्वयं उनके बारे में निर्णय कर लेगी। हम लोग उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते।

माया : उनका कहना है कि आपने जनमोर्चा नहीं 'जंग मोर्चा' बनाया है।

रामधन : वह कुछ भी कहें। किसी भी नाम का कोई भी भाष्य किया जा सकता है, कोई उलटा अर्थ लगाया जा सकता है।

माया : क्या आप जनमोर्चा या जंग मोर्चा से नयी लड़ाई शुरू करेंगे ?

रामधन : हम तो समझते हैं कि यह आजादी के बाद की दूसरी लड़ाई है। पर इसे जंग मोर्चा नहीं कहा जा सकता। हमारा जो मोर्चा होगा, वह संघर्ष तो करेगा, लेकिन जंग जिस शाब्दिक अर्थ में लिया जाता है, वैसा नहीं करेगा।

माया : मोर्चे का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

रामधन : इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे हम समाज में व्यवस्था-परिवर्तन लाना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सत्ता-परिवर्तन की बातें तो की जाती हैं, पर व्यवस्था-परिवर्तन की नहीं।

माया : यदि यह परिवर्तन राजीव गांधी के सत्ता में रहते हो सके, तो क्या सरकार से आपकी लड़ाई समाप्त हो जायेगी ?

रामधन : राजीव गांधी के रहते इस परिवर्तन की संभावना ही नहीं है। सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं।

माया : आप तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के पहले कांग्रेस से जुलाई, १९८६ में इस्तीफा देकर अलग हो गये थे। क्या बात आपको बहुत खली थी जो आपने ऐसा किया था ?

रामधन : एक तो राजीव गांधी की कार्यप्रणाली इंदिरा गांधी की कार्यप्रणाली से बहुत अलग थी। राजीव गांधी की कार्यप्रणाली काफी दोषयुक्त मुझे दिखायी पड़ी। अधिक समय तो नहीं, पर छह महीने तक एक पदाधिकारी के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था। उस दौरान उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर देखने को मिला। बातचीत में जो वह तय करते थे, उसके विपरीत कार्य करते थे। कथनी-करनी में अंतर के अलावा मुझे लगा कि वह काफी गलतबयानी भी करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे आभास हुआ कि उनके साथ काम करने का माहौल नहीं है। उनकी अराजनीतिक दृष्टि और अपरिपक्व मस्तिष्क के कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा होती थीं। अ०भा० कांग्रेस कमेटी एक जीरो थी। वहां के पदाधिकारियों को काम करने की कोई आजादी नहीं थी। जो भी आदेश उनके (राजीव) राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार से मिलते थे, उसी को पूरा करने की छूट थी।

माया : उस समय तो अर्जुन सिंह उपाध्यक्ष थे और यह कहा जाता है कि खुद अर्जुन सिंह आदेश देते थे ?

रामधन : अर्जुन सिंह और फोतेदार दोनों से जो कहा जाता था, वही हम लोगों को आदेश मिलते थे।

माया : तो क्या अर्जुन सिंह को भी स्वतंत्रता नहीं थी ?

रामधन : हां, अर्जुन सिंह तो हमेशा कहते रहे हैं कि हम तो हुक्म बजाने वाले हैं, जो कुछ हमें कहा जाता है, हम करते हैं। इसीलिए जब दो दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यपाल बनाया गया, तो उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि जो भी आदेश मिलेगा, उसका सहर्ष पालन करेंगे।

माया : क्या कोई ऐसी व्यक्तिगत बात भी थी, जिससे आपको निराशा हुई ?

रामधन : नहीं। किसी व्यक्तिगत बात का सवाल ही नहीं था। मैं मानता था कि कांग्रेस का वोट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। पिछले ४० वर्षों में उनके लिए जो भी कार्य किये गये, वे संतोषजनक नहीं हैं। सारी योजनाओं का कार्यभार भी कांग्रेस पर है और उनका कार्यान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति मुझे पूरी तरह से देखने को मिली। मैं जब अ०भा० कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया था तो उस समय मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने का विशेष कार्य सौंपा गया था, क्योंकि उत्तर भारत में एक बहुजन समाज पार्टी है। यह संस्था उभर रही है और उ०प्र० के कुछ उपचुनावों में उसको काफी वोट मिले थे। इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि

राजीव गांधी की कार्यप्रणाली काफी दोषयुक्त मुझे दिखायी पड़ी। छह महीने तक एक पदाधिकारी के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था। उस दौरान उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर देखने को मिला

उ०प्र० में अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के करीब आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह (हरिजन) कांग्रेस से जुड़े रहें, इसके लिए प्रयास करना जरूरी था। इस प्रकार मुझे एक चुनौतीपूर्ण कार्य मिला था। मैंने समझा था कि इस दिशा में स्वतंत्र रूप से एकनिष्ठ होकर काम करने का मुझे अवसर मिलेगा। किंतु जब मैंने अ०भा० कांग्रेस कमेटी का माहौल देखा, तो पता चला कि वहां कोई प्रणाली, कोई परिपाटी नहीं है। इससे मुझे झटका लगा। किंतु सबसे बड़ा आघात मुझे राज्यसभा के चुनावों के दौरान उ०प्र० के उम्मीदवारों के चयन के समय लगा। एक ओर तो हम बहुजन समाज पार्टी की चुनौती का सामना कर रहे थे, दूसरी ओर हमारे जो वर्तमान हरिजन सदस्य थे, उनको समुचित स्थान नहीं दिया जा रहा था। उ०प्र० से राज्यसभा के तीन हरिजन सदस्य थे। इनमें से एक का समय दो वर्ष के लिए और दूसरे का मात्र छह महीने के लिए ही था। हमारी मांग थी कि ये तीनों स्थान अनुसूचित जाति के लोगों को मिलें और अन्य राज्यों में चयन के समय भी इस वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। लोकसभा और विधानसभा की सीटें सुरक्षित हैं, इसलिए वहां उन्हें स्थान मिल जाता है। किंतु राज्यसभा और विधान परिषद में यह संरक्षण प्राप्त नहीं है और पार्टियों के गुडविल (सद्भाव) से यह प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिले, यही मैं चाहता था। फिर बहुजन पार्टी का नारा था, पिछड़े वर्गों की सत्ता में भागीदारी हो। इसलिए मैंने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में हमारा समुचित प्रतिनिधित्व रहेगा, तो इन वर्गों को संतोष रहेगा। लेकिन कार्य इसके बिलकुल विपरीत हुआ। मेरी राजीव गांधी से केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के पहले बात हुई थी और मैंने उन्हें यह लिखकर दिया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ये तीनों स्थान अनुसूचित जातियों को ही दिये जायेंगे किन्तु हो सकता है उम्मीदवारों के नामों में परिवर्तन किये जायें। मैंने कहा कि आपको इसकी पूरी आजादी है, यदि वर्तमान सदस्यों के कार्य संतोषजनक नहीं हैं, तो अनुसूचित जाति के ही दूसरे उम्मीदवारों का चयन कर लें। मगर इनकी संख्या किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वायदा किया। दूसरे दिन केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जो रात ११ बजे तक चली। उसमें केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि तीन की जगह दो स्थान पर ही अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चयन किया जाये। लेकिन इसके फैसले को भी रात १२ बजे बदल दिया गया। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के निर्णय को कोई चोरी-छिपे बदल दे। हुआ यह कि जो दो उम्मीदवार तय हुए थे, उनमें एक हरी सिंह बाल्मीकि का नाम था। हमारी मान्यता रही है कि अनुसूचित जाति में भी विभिन्न वर्गों—बाल्मीकि, जाटवों आदि को प्रतिनिधित्व मिले। किंतु सब लोगों को तब भारी आश्चर्य हुआ, जब हरी सिंह बाल्मीकि का नाम काट करके कल्पनाथ राय जैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। दरअसल कल्पनाथ राय को पार्टी की मान्यताओं के विपरीत टिकट दिया गया।

माया : ऐसा क्यों किया गया ?

रामधन : यह राजीव गांधी और उनके लोग ही बता सकते हैं।

माया : आपने कुछ जानने की कोशिश नहीं की ?

रामधन : नहीं। मैं उसी दिन मद्रास जा रहा था और इसके विरोध में मैंने तत्काल पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। फोतेदार ने दो-तीन बार मुझे फोन किया कि वह मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं किसी सलाहकार से बात नहीं करूंगा। यदि राजीव गांधी बात करना चाहें, तो मैं तैयार हूं। पर इसकी नौबत नहीं आयी। और मेरे त्यागपत्र की आज तक प्राप्तिसूचना भी नहीं दी गयी। बाद में कुछ समाचारपत्रों व पत्रकारों से ज्ञात हुआ कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

माया : उनका (राजीव गांधी का) ख्याल रहा होगा कि श्रीमती मीरा कुमार को उन्होंने सांसद बनाया है और वह यह काम संभाल लेंगी ?

रामधन : उनके मन में क्या था, मैं क्या जानूं। पर उनकी कार्यशैली में यही सब कमियां हैं। ऐसी कार्यप्रणाली इस बात का द्योतक है कि वह मनमाना कुछ भी निर्णय कर सकते हैं। इससे एक जबर्दस्त आघात मुझे यह लगा कि जिस पार्टी के सर्वोच्च संसदीय मंडल के निर्णय चोरी-छिपे बदल दिये जाते हैं, और कल्पनाथ राय को एकाएक टिकट दे दिया जाता है, उसका क्या ठिकाना ? इसके अलावा दूसरे राज्यों में ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया था जो दो बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे, फिर कल्पनाथ राय को तीसरी बार राज्यसभा का टिकट क्यों दिया गया ?

माया : जगजीवन राम जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ लगभग ४० वर्ष रहकर भी अनुसूचित जातियों-जनजातियों को थोड़ा ही आगे बढ़ा पाये। क्या आपको उम्मीद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ रह कर आप कुछ कर सकेंगे ?

रामधन : जगजीवन राम राष्ट्रीय आंदोलन में अवश्य आये थे। पर आजादी के बाद सरकार बनी, तो उन्हें बराबर मंत्री-पद मिलता रहा। इसका फल यह हुआ कि जगजीवन राम ने मंत्री-पद के दायरे से निकल कर कभी संघर्ष नहीं किया। इन पिछड़े वर्गों का नेतृत्व करने की उन्होंने वह कोशिश नहीं की, जैसी बाबा साहब अंबेडकर ने सत्ता से और पद मुक्त होकर किया था। इस प्रकार जगजीवन राम की जगह श्री अंबेडकर अनूसूचित जातियों के मसीहा बन गये। लगभग ४० वर्ष तक जगजीवन राम केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहे, पर वह इन वर्गों को संगठित नहीं कर पाये। १९८० में जब हम लोगों ने उन्हें जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया, तो उनके पुत्र के आग्रह पर घोषणापत्र में लिखा दिया गया कि जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री होंगे। यह लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत था क्योंकि जब चुनाव होता है, तो जो पार्टी जीतती है उसके नेता-पद का चुनाव होता है। किंतु उन्होंने इस बात को पक्का रखने के लिए कि कोई दूसरा उम्मीदवार न हो, घोषणा पत्र में यह बात लिखवा दी और हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा। उस दौरान भी मैंने देखा कि उनको हरिजनों के वोट का अधिकांश भाग तो मिला, पर कांग्रेस का जो पारंपरिक हरिजन वोट था—लगभग १०-१५ प्रतिशत, वह इंदिरा गांधी के साथ गया। इस प्रकार जगजीवन राम ने कभी भी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को संगठित करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनकी राजनीति सुविधा की राजनीति थी। वह अंबेडकर की भांति दलितों, वंचितों के जुझारू नेता बनकर नहीं उभरे।

माया : कांग्रेस में आपको हरिजनों, पिछड़े वर्गों को संगठित करने का काम सौंपा गया था। क्या मोर्चे में भी आपको ऐसी जिम्मेदारी दी गयी है ?

रामधन : मैं तो पूरे मोर्चे का संयोजक बनाया गया हूं। किसी विशेष कार्य की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी गयी।

माय्या : क्या किसी और को यह काम आपके मोर्चे में सौंपा गया है ?

रामधन : मोर्चे में एकमात्र पद संयोजक का है और वह भी तदर्थ (एडहाक) रूप में। ऐसी हालत में अन्य काम फिलहाल किसी को नहीं सौंपा गया।

माया : क्या राज्यों में भी संयोजक बनाये जायेंगे ?

रामधन : न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि जिला स्तर पर भी संयोजक बनाये जायेंगे।

माया : एक करोड़ सदस्य बनाने का जो आपका अभियान है, क्या यह पूरा हो जायेगा ?

रामधन : हमारे पास रोज सदस्य बनाने की भारी संख्या में मांग आ रही है। इसको पूरा करने के लिए हमारे पास फार्म नहीं हैं। राजस्थान, म०प्र०,

बढ़ते बच्चों की ज़रूरत कॉम्प्लान

सिर्फ़ कॉम्प्लान में ही २३ अत्यावश्यक पोषक तत्त्व हैं जिनकी उनको रोज़ाना ज़रूरत है.

साधारणतया १५ या १६ की उम्र तक बच्चों के शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है.

शरीर के विकास में जो पोषक तत्व सीधे सहायक होते हैं वे प्रोटीन हैं. इसीलिए आपके बच्चों को **कॉम्प्लान** की ज़रूरत इसी समय है. **कॉम्प्लान** में सर्वोत्तम प्रोटीन-दुग्ध प्रोटीन (२०%) है. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, स्निग्ध पदार्थ, विटामिन्स और खनिज पदार्थ जैसे २२ अन्य अत्यावश्यक पोषक तत्व भी हैं; जिनकी बच्चों को बढ़ती उम्र में ज़रूरत रहती है. अपने बच्चों को **कॉम्प्लान** दीजिए; हर रोज, दिन में दो बार.

कॉम्प्लान चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, इलायची-केसर और आइस्क्रीम के स्वादभरे ज़ायकों में तथा प्लेन भी मिलता है. बच्चों को तो बस स्वाद भा जाए!

Complan
COMPLETE PLANNED FOOD
CHOCOLATE FLAVOUR
No need to add milk

23

२३ अत्यावश्यक पोषक तत्व नियोजित मात्रा में

प्रोटीन
फैट
कार्बोहाइड्रेट
कैल्सियम
फॉस्फोरस
सोडियम
क्लोराइड
(सी एल के रूप में)
पोटासियम
आयरन
आयोडिन
विटामिन ए
विटामिन बी १

रिबोफ्लेविन
निकोटिनामाइड
कैल्सियम
पैन्टोथेनेट
कॉलिन
पायरिडॉक्सीन (बी ६)
विटामिन बी १२
फॉलिक एसिड
विटामिन सी
विटामिन डी
विटामिन ई
विटामिन के

दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं.

कॉम्प्लान® — परिपूर्ण नियोजित आहार

GX/35/244 HIN

हरियाणा, उ०प्र० से लोग रोज आते हैं, फोन से संपर्क करते हैं। मसलन, झुंझनू (राजस्थान) से रात ११ बजे फोन आया कि ५० हजार फार्म तुरंत भेजिए।

माया: जनता पार्टी के महासचिव यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वी०पी० सिंह जो कहते आये हैं वह आपके घोषणापत्र में नहीं है—मसलन वह कोई पद नहीं लेंगे।

रामधन: यह पद न लेने का कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। यह व्यक्तिगत चीज है। कांग्रेस का विकल्प क्या है, यह फैसला जनता करेगी। यदि जनता यह निर्णय करती है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का नेतृत्व संभालें, तो उन्हें यह बात माननी पड़ेगी।

माया: यह तो आप कह रहे हैं?

रामधन: गत दिनों मैंने अपने सहयोगियों के मध्य बातचीत करते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा था कि आप इस तरह की सार्वजनिक घोषणा न करें। उनकी असहमति पर मैंने जब कहा कि आप मुझे मोर्चे का संयोजक बना रहे हैं, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पर जोरदार ठहाका लगा। यह मुद्दा तो समय की अनिवार्यता पर निर्भर करता है।

माया: यह बात ड्राइंगरूम तक नहीं आप लोगों में भी फैल रही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कोई दिशा नहीं पकड़ रहे हैं। कुछ इधर भी, कुछ उधर भी और यह बात राजीव गांधी के पक्ष में जा रही है। क्या वास्तव में विश्वनाथ प्रताप सिंह दिशाहीन अथवा दिग्भ्रमित हैं?

रामधन: मैं तो अपने ५० साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह दिशाभ्रमित नहीं हैं।

माया: यह आप कैसे कह रहे हैं?

रामधन: हम लोगों में विचारों के मंथन के दौरान बहुत सी बातें आती थीं। यह एक तदर्थ काल है, जिसमें बहुत-सी बातें-विचार उभरकर आते हैं। मगर हम लोगों ने एक ठोस कार्यक्रम भी बनाया है। हम मुद्दों से इधर-उधर जाना नहीं चाहते हैं। हमने इसके लिए जनसंघर्ष का फैसला किया है। इस प्रकार भ्रांति की बात बेबुनियाद है।

माया: जब लोगों की भीड़ आप लोगों को सुनने आती है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है?

रामधन: जब श्रोताओं के सामने हम विभिन्न मुद्दों की बात उठाते हैं, तो उन पर इतना असर नहीं पड़ता। श्रोता, मीडिया और जनता का सर्वाधिक ध्यान भ्रष्टाचार पर जाता है।

माया: क्या आप लोग केवल भ्रष्टाचार की बात से दो साल खींच लेंगे?

रामधन: हम यह नहीं मानते कि राजीव गांधी दो साल चलेंगे। बोफोर्स में अगर नाम आ जाते हैं, तो जनता उन्हें गद्दी छोड़ने को बाध्य कर देगी।

माया: नाम आने की उम्मीद आपको है?

रामधन: उम्मीद पर दुनिया कायम है।

माया: दिशाभ्रमित होने का आरोप आपके घोषणापत्र पर भी लगाया जाता है?

रामधन: यह घोषणा पत्र नहीं है। न हमारी कोई पार्टी है न घोषणा पत्र। हम चंद सीमित मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। जब हमारी शक्ति का विस्तार हो जायेगा, तब हम विस्तृत मुद्दों को उठायेंगे।

हम जनचेतना पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार यह विभाजन कर्म पर होगा। यह कहना भी गलत है कि हम थोड़े से लोग हैं। क्योंकि थोड़े से लोग भी परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। हम लोग जब कांग्रेस में थे, तो कुल चार युवा तुर्क थे—चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, चन्द्रजीत यादव और मैं और उस समय कांग्रेस की नीति में परिवर्तन ले आये।

माया: गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एकमात्र मुद्दा आजादी का उठाकर १९४५ तक एक आंदोलन चलाया था और उसमें विभिन्न विचारधारा के लोग मसलन नेताजी, जवाहर लाल नेहरू, कृपलानी, राजेन्द्र प्रसाद आदि शामिल थे। क्या उसमें और आपके मोर्चे में समानता है?

रामधन: यह बहुत उत्तम सवाल है। जनमोर्चा के गठन के अवसर पर मैंने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा देश को आजाद कराया था, उस समय का जीवन मूल्य कार्यकर्ताओं में तुरंत स्थापित कराना चाहिए क्योंकि राजनीति आज व्यवसाय बन गयी है। जो आज राजनीति में आता है, उसे कल अवश्य कुछ चाहिए। जब मैं १९४२ में राष्ट्रीय आंदोलन में आया था, तो घरबार छोड़कर पूर्णकालिक पार्टी कार्यकर्ता बनकर मैं जेल भी गया था। उस समय हमारा एकमात्र लक्ष्य आजादी का था। हमने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि हम विधायक या सांसद बनेंगे या सत्ता के उच्च पदों पर जाने का मौका मिलेगा। १९४८ में मैं जब निर्विरोध विधानसभा सदस्य बन रहा था, तब मैंने अपना नामांकनपत्र वापस ले लिया था और दूसरे को विधायक होने दिया था। क्योंकि मैं जेल से छूटकर आने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। ऐसी भावना थी उन दिनों। आज स्थिति बदली हुई है। हम उन्हीं मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं। उस समय हम भूखे रहकर, पैदल चलकर आजादी की लड़ाई में शामिल थे। हमारे सामने एक मिशन था।

माया: क्या आज ऐसा मिशन देखने में आता है?

रामधन: कुछ कार्यकर्ताओं में अवश्य है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह उसका लोप हो गया। किंतु जब मान्यता बदलती है, तो लोगों के विचार और रहन-सहन तक बदल जाते हैं।

माया: गांवों के अनपढ़ लोग जो प्रेस से पूरी तरह अप्रभावित हैं, क्या भ्रष्टाचार की बात समझ राजीव गांधी को हटाने को तैयार हो जायेंगे?

रामधन: उच्चतम स्तर का नहीं, तो निम्नतम स्तर का भ्रष्टाचार उन्हें अवश्य प्रभावित कर रहा है। दियासलाई, केरोसिन से लेकर कचहरी, सरकारी दफ्तरों और ऋण प्राप्ति में फैले भ्रष्टाचार से वे बुरी तरह परेशान हैं। देश की जनता अनपढ़ होते हुए भी राजनीति को भलीभांति समझती है और हमारा उसपर पूरा भरोसा है कि वह सही फैसला लेगी। **जब आप मानते हैं कि जनता राजनीति को समझती है, तो अपने मोर्चे को आप ने अराजनीतिक क्यों बनाया है?**

रामधन: हमारा मोर्चा राजनैतिक है, पर पार्टी नहीं है। पार्टी का संविधान, नियम, घोषणापत्र होता है। हम कुछ मुद्दों को लेकर जनांदोलन चला रहे हैं।

मायाः बाद में आप इसे पार्टी का रूप देंगे?

रामधन: उस समय की स्थितियों के अनुसार विचार किया जायेगा।

माया: कांग्रेसी कहते हैं कि पार्टी छोड़कर अनेक लोग गये, जैसे वाई०बी० चह्वाण, प्रणब मुखर्जी, गुंडूराव आदि। पर उनकी कोई विशेष साख जनता में नहीं रही और आप लोगों का भी यही हश्र होगा।

रामधन: उन लोगों ने केवल सत्ता के लिए कांग्रेस छोड़ी थी। अब समुचित कारणों से विभाजन हो रहा है जो जनाधार पर होगा। हम जन चेतना पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार यह विभाजन कर्म पर होगा। यह कहना भीं गलत है कि हम थोड़े से लोग हैं। क्योंकि थोड़े से लोग भी परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। हम लोग जब कांग्रेस में थे, तो कुल चार युवा तुर्क थे—चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, चन्द्रजीत यादव और मैं और उस समय कांग्रेस की नीति में परिवर्तन ले आये। मोरारजी देसाई के कट्टर विरोध के बावजूद राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रीवीपर्स खतम हुआ। जब हम लोगों ने संघर्ष किया कि श्रीमती गांधी को जयप्रकाश नारायण से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, तो भी हम चार ही लोग थे। उस सिलसिले में कांग्रेस संसदीय दल के सचिव होते हुए मुझे आपातकाल के पूर्व ही मीसा में जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार यह बात गलत है कि थोड़े से लोग देश की जनता को जाग्रत करने में अक्षम हैं। उस समय जनता में इतना उभार भी नहीं था। पर आज तो वह जात-पांत और विचारधारा की सीमाएं तोड़ कर एक साथ आ रही है। ■

हरिया की ख़ुशहाली का राज़

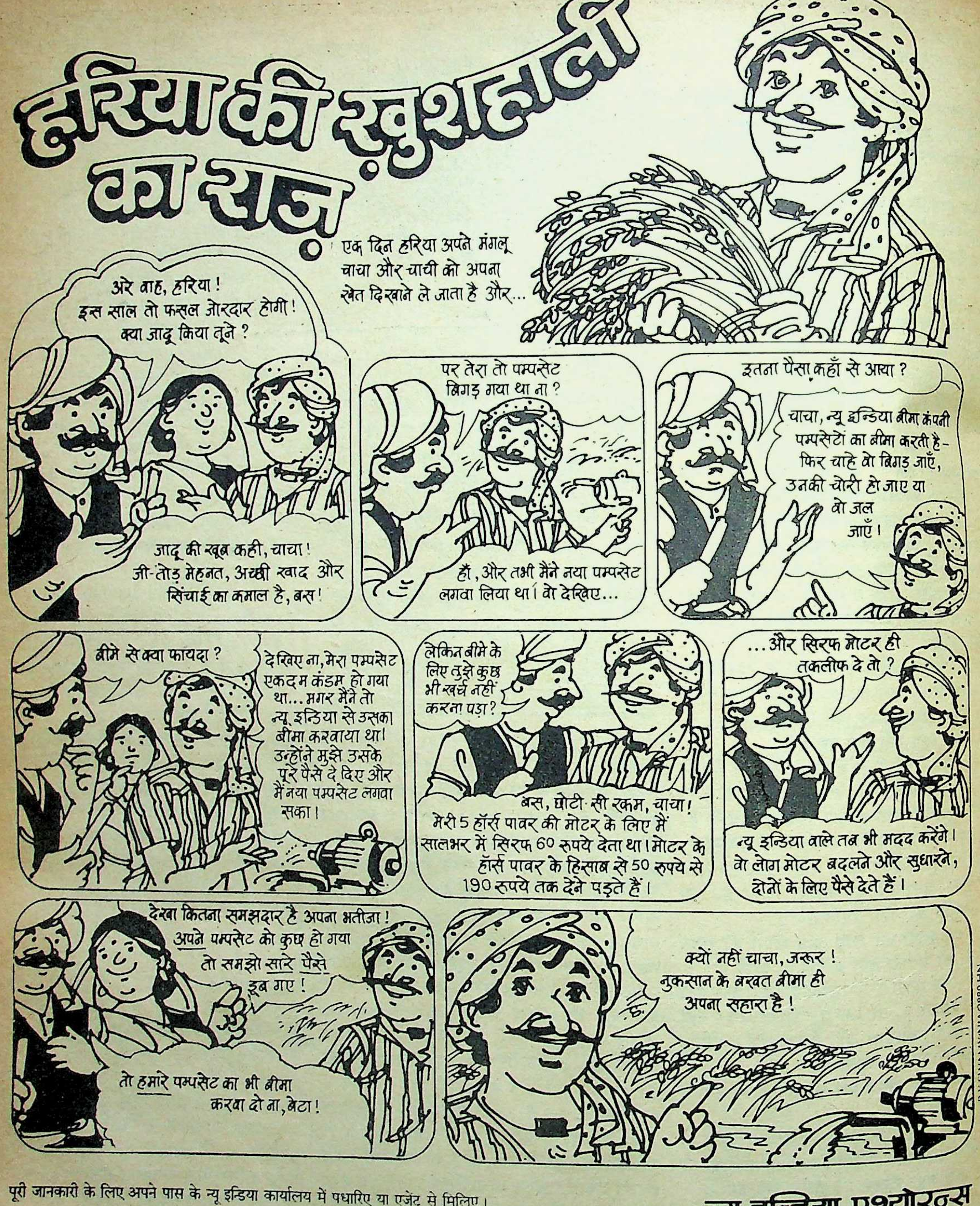
एक दिन हरिया अपने मंगलू चाचा और चाची को अपना खेत दिखाने ले जाता है और...
अरे वाह, हरिया! इस साल तो फसल जोरदार होगी! क्या जादू किया तूने?
जादू की खूब कही, चाचा! जी-तोड़ मेहनत, अच्छी खाद और सिंचाई का कमाल है, बस!
पर तेरा तो पम्पसेट बिगड़ गया था ना?
हाँ, और तभी मैंने नया पम्पसेट लगवा लिया था। वो देखिए...
इतना पैसा कहाँ से आया?
चाचा, न्यू इन्डिया बीमा कंपनी पम्पसेटों का बीमा करती है - फिर चाहे वो बिगड़ जाएँ, उनकी चोरी हो जाए या वो जल जाएँ।
बीमे से क्या फायदा?
देखिए ना, मेरा पम्पसेट एकदम कंडम हो गया था... मगर मैंने तो न्यू इन्डिया से उसका बीमा करवाया था। उन्होंने मुझे उसके पूरे पैसे दे दिए और मैं नया पम्पसेट लगवा सका।
लेकिन बीमे के लिए तुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा?
बस, छोटी-सी रकम, चाचा! मेरी 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए मैं सालभर में सिर्फ 60 रुपये देता था। मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से 50 रुपये से 190 रुपये तक देने पड़ते हैं।
...और सिरफ मोटर ही तकलीफ दे तो?
न्यू इन्डिया वाले तब भी मदद करेंगे। वो लोग मोटर बदलने और सुधारने, दोनों के लिए पैसे देते हैं।
देखा कितना समझदार है अपना भतीजा! अपने पम्पसेट को कुछ हो गया तो समझो सारे पैसे डूब गए!
तो हमारे पम्पसेट का भी बीमा करवा दो ना, बेटा!
क्यों नहीं चाचा, जरूर! नुकसान के वखत बीमा ही अपना सहारा है!
R K SWAMY/NIA/2880 HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इन्डिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया की एक सहायक कंपनी

बीमा — नुकसान में आपका सहारा!

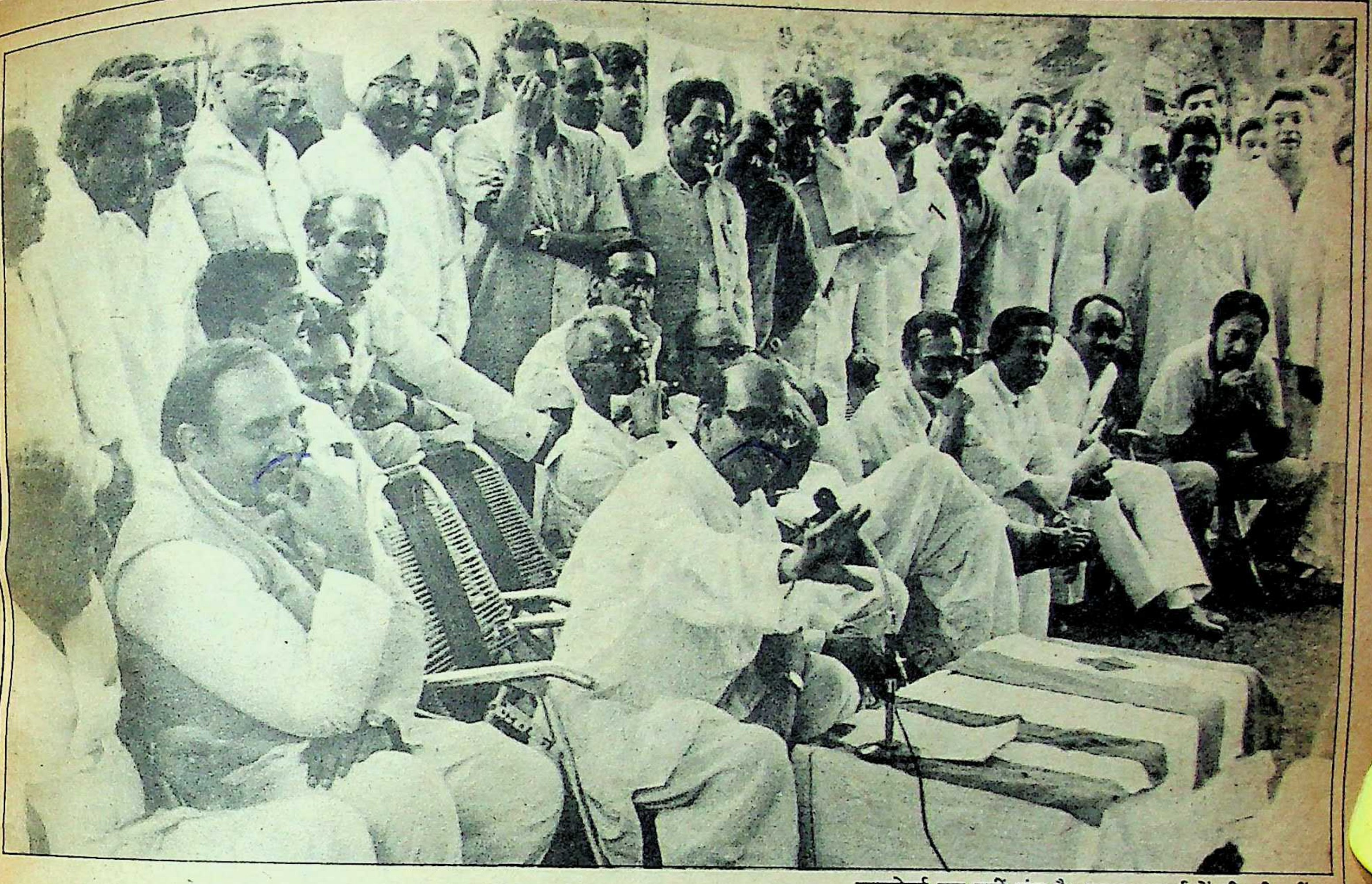

जनमोर्चा दल नहीं मंच है: पत्रकारवार्ता में वी०पी० सिंह

वी०पी० सिंह का 'जनमोर्चा'

जन, जंग या 'जंक'?

निश्चित रूप से मोर्चे की शुरुआत में—कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की पहली जनसभा में ५० हजार और फिर पटना के गांधी मैदान में एक लाख से ऊपर की भीड़ इकट्ठी होना—प्रेरणाप्रद है। किंतु यही जनसमुदाय मोर्चे की अनुपस्थिति में केवल वी०पी० सिंह के नाम पर ही एकत्र हो जाता, इसमें लेशमात्र संदेह नहीं। अब तक की सभी सभाओं में ऐसा होता रहा है, चाहे स्थान गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार रहा हो या इस्पात नगरी भिलाई। तात्पर्य यह है कि वी०पी० सिंह अभी भी आकर्षण के केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं। प्रश्न यह है कि फिर जनमोर्चा की स्थापना क्या केवल उन आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए की गयी, जो 'राजा साहब' के सैलाब को दिशाहीन, भ्रमित और अव्यवस्थित आदि विशेषणों से सुशोभित कर रहे थे? ऐसी स्थिति में इस मोर्चे के स्वरूप और भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर ने सर्वथा सही कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा। अतः वी०पी० सिंह गुट द्वारा नवगठित मोर्चे को चाहे जनमोर्चा कहें या जंग (युद्ध) अथवा इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद के शब्दों में इसे 'जंक' (कबाड़) मोर्चा करार दें, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कारण स्पष्ट है। आज भी मोर्चे को विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम और छवि से पृथक कर पाना असंभव है। विचाराधीन बात यह है कि यद्यपि परोक्ष रूप में वी०पी०सिंह की हैसियत मोर्चे के एक साधारण कार्यकर्ता की ही है (संयोजक जुझारू हरिजन नेता रामधन हैं), किंतु जनमोर्चा का संपूर्ण भविष्य उनके जन जागरण अभियान की सफलता पर ही निर्भर है। निर्भरता पारस्परिक नहीं है। वी०पी० सिंह के कंधे अभी भी अधिक बोझिल हैं। शायद यही कारण है कि मोर्चे की स्थापना से विपक्षी खेमों में या स्वयं कांग्रेस शिविर में कोई विशेष उथलपुथल फिलहाल नहीं हुई है। मौके की तलाश में टकटकी लगाये रखने का पूर्व प्रचलित खेल अभी जारी है।

विपक्ष की अधिकांश पार्टियों ने तो मोर्चे के जन्म को विकास प्रक्रिया की एक कड़ी बताते हुए उनका स्वागत भी किया है। जनता पार्टी के महासचिव यशवंत सिन्हा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है, "व्यक्तियों के बिखरे समूह का एक संगठन बन जाने से विपक्ष को उसके साथ संबंध

खुशख़बरी—लिनोलियम की ओर से...

लिनोलियम आपके घर के लिए एक आदर्श फ़र्श-बिछावन है। बिछाने व रख-रखाव में बेहद आसान। प्राकृतिक द्रव्यों से निर्मित लिनोलियम स्वच्छ व स्वास्थ्यकर तो है ही, बल्कि ध्वनिरोधक और टिकाऊ भी। एक ही पोंछे में चमक उठे और वर्षों तक नया ही नज़र आए। आकर्षक डिजाइनों, रंगों व मोटाई के अद्भुत संगम में से अपने मनपसंद का फ़र्श-बिछावन चुनिए। अपने रूपयों की पूर्ण अदायगी के लिए आपकी पसंद लिनोलियम ही होनी चाहिए।

लिनोलियम

एक शानदार बहु-उपयोगी फ़र्श-बिछावन

इण्डिया लिनोलियम्स लिमिटेड
९/१, आर. एन. मुखर्जी रोड़, कलकत्ता-७०० ००१

CC/IL/1/87 HIN

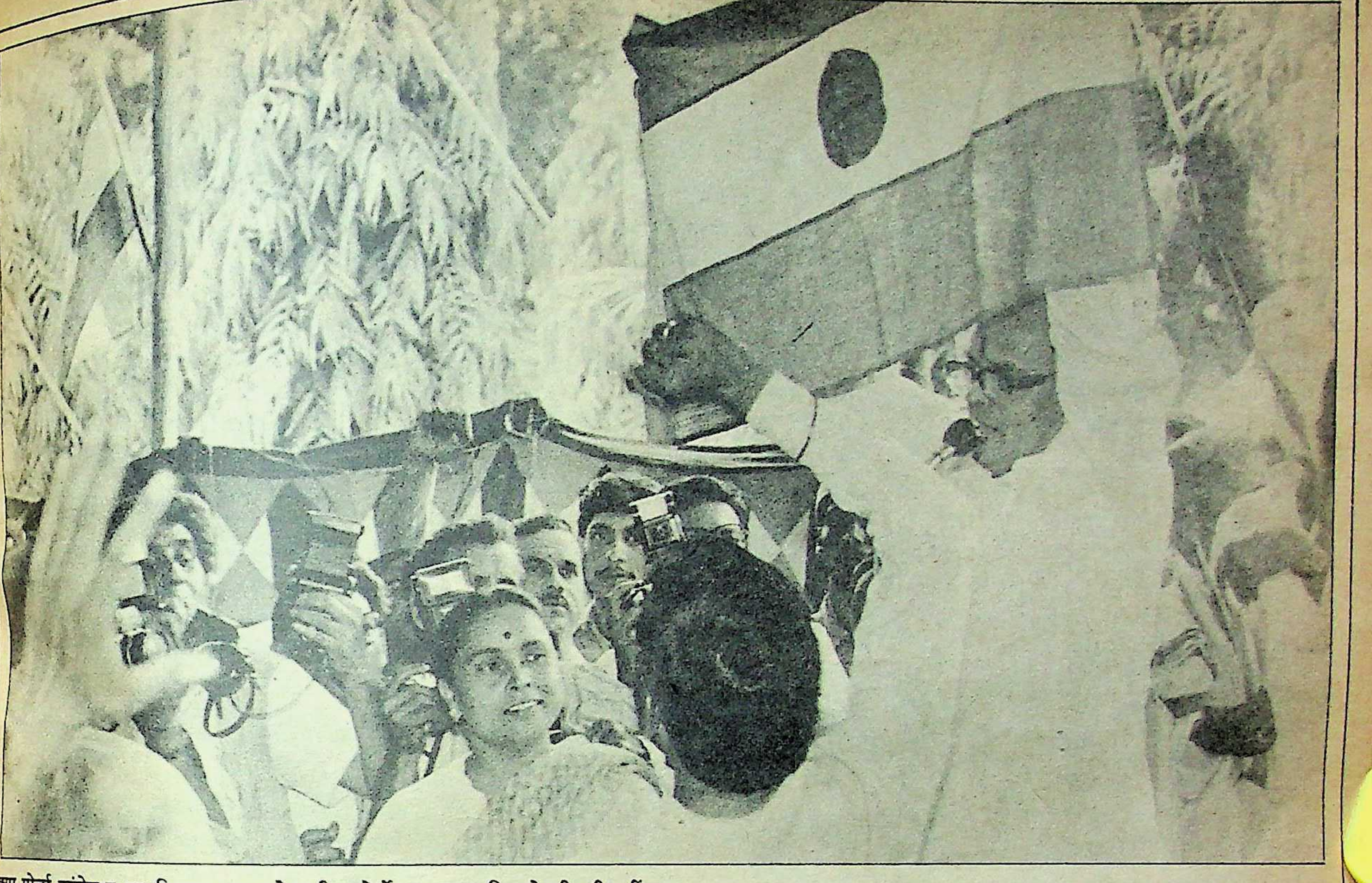

क्या मोर्चा कांग्रेस-इ का विकल्प बन सकेगा ? : मोर्चे का झण्डा दिखाते वी०पी० सिंह

बनाने में अधिक सुविधा होगी।" कांग्रेस द्वारा भर्त्सना अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि मोर्चा संभालने वाले सभी नेता पुराने, असंतुष्ट कांग्रेसी हैं। अतः महासचिव आजाद द्वारा मोर्चा को जंक (कबाड़), वी०पी० सिंह को ढुलमुल विचारों वाला और संयोजक रामधन को 'गिरगिट' करार देना कांग्रेस के रोष प्रदर्शन का एक अनूठा नमूना है। अप्रत्याशित है तो भाजपा की चुप्पी जो उन्होंने निश्चय ही जानबूझकर साधी है, क्योंकि कांग्रेस की तरह उसने इस बात का भी तो डंका नहीं पीटा है कि उसे जनमोर्चा के जन्म की रत्ती भर परवाह नहीं है। भाजपा को चिन्ता इस बात की है कि कहीं वामपंथ को अपना 'स्वाभाविक सहयोगी' प्रचार करते-करते वी०पी० सिंह और जनमोर्चा वास्तव में ही उनके साथ न हो जायें। यही कारण है कि मोर्चे पर सीधा बयान न देते हुए उन्होंने वामपंथ पर उसे गुमराह करने और उसका उसी प्रकार उपयोग करने का आरोप लगाया है, जिस प्रकार उसने बंगाल में सातवें दशक के अंतिम वर्षों के दौरान एक अन्य असंतुष्ट कांग्रेसी नेता अजय मुखर्जी का उपयोग किया था।

स्वरूप विवादास्पद : मोर्चे की स्थापना से कहीं अधिक चर्चा रही है उसके स्वरूप की, जिसके अराजनीतिक होने की घोषणा ने सभी राजनीतिक दलों को हक्का-बक्का कर दिया है। यदि मोर्चे के नेताओं के विचारों को स्वीकारा जाये, तो यह मोर्चा विशिष्ट मुद्दों के आधार पर मुहिम चला, व्यापक जनमत बनाकर देश के राजनीतिक परिदृश्य में मौलिक परिवर्तन लायेगा। चूंकि ध्येय राजनीतिक है, इसलिए मोर्चे के अराजनीतिक होने के दावे को कांग्रेस ही नहीं विपक्ष भी किसी प्रकार मानने को तैयार नहीं।

जनता पार्टी के विचारों को 'माया' के सामने रखते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वरूप को स्वीकार करने में मोर्चे को किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्यों और कार्यक्रमों के प्रति मोर्चे की झिझक को समझ पाने में मैं असमर्थ हूं। आशा है कि निकट भविष्य में ही जनमोर्चा इस बात को स्वीकारेगा कि राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र का एक अभिन्न, अविभाज्य और आवश्यक अंग है।

भाजपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जनमोर्चा को अपने दल द्वारा अनदेखा करने की वर्तमान नीति पर प्रकाश डालते हुए स्वीकारा कि यह इस बात का द्योतक है कि भाजपा मोर्चे को एक अन्य राजनीतिक दल मानने लगा है। जाहिर है कि उसके प्रति भाजपा का वही व्यवहार होगा जो अन्य दलों के प्रति है। दोनों लोकदल (अ और ब) का भी मत कुछ इसी प्रकार का है। हालांकि लोकदल (अजीत) के महासचिव सुब्रह्मण्यम स्वामी के लिए अधिक चिन्ता का विषय यह है कि वी०पी० सिंह और उनका यह मोर्चा किस दिशा में अग्रसर है। इसका खुलासा स्पष्ट रूप से मोर्चे के गठन के बाद भी नहीं हुआ है। मोर्चे के विरुद्ध अस्पष्ट और भ्रामक होने के आरोप कांग्रेसी खेमे से भी निरंतर लग रहे हैं। यदि गुलाम नबी आजाद इसकी पुष्टि का कारण किसी भी नये या अनूठे कार्यक्रम का अभाव मानते हैं तो उनके साथी महासचिव केदार नाथ सिंह तो मोर्चे को—'जनता के साथ सरासर धोखा' करार देते हैं। उनके अनुसार, "जब झंडा अलग, डंडा अलग, अनुशासन अलग, फीस एक रुपए अलग, घोषणापत्र छप गया, तब भी वह कहें कि हम मंच हैं, दल नहीं तो दल बनाते समय वह क्या कहेंगे ?" श्री सिंह का मानना है कि मोर्चे का यह कार्य और रुख अनैतिक है, "मथुरा में कांग्रेस को समाप्त करने का डंका पीट कर उन्होंने मेरे कहे की और पुष्टि कर दी है।"

तर्कसंगत विवाद : वर्तमान अस्पष्ट स्थिति के कारण अन्य तर्कसंगत विवाद भी हैं। कहा जाता है कि देश की राजनीतिक मूलधारा में जुड़ने के दो प्रमाणित रूप मौजूद हैं—प्रथम जयप्रकाश नारायण का माडल, जिसके तहत अभियान को सत्ता और व्यवस्था से पूर्णतया परे रखकर लोकशक्ति के सहारे एक दबाव बिन्दु के रूप में कार्य करना। जे० पी० के केस में स्वरूप सुनिश्चित और स्पष्ट रहा, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह स्वयं अंत तक इसी रूप को अपनाये रहे।

दूसरा माडल उन आंदोलनों का है जो बाद में

राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गये, जैसा कि अखिल असम छात्र परिषद (आसू) ने असम गण परिषद (एजीपी) बनकर किया। दुर्भाग्यवश जनमोर्चा दोनों में से एक भी माडल को अपनाने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि उसकी और उसके सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की छवि राजनीतिक है। यही कारण है कि यशवन्त सिन्हा सहित अन्य विपक्षी नेता जनमोर्चा द्वारा अपने को अराजनीतिक घोषित और सिद्ध करने के प्रयास को व्यर्थ और बचकाना मानते हैं।

यद्यपि विभिन्न दलों में स्वाभाविक मतभेद हैं, लेकिन लगभग सभी दल एक अन्य मुद्दे पर भी सहमत हैं—वह है मोर्चे को दल न बनाकर मंच ही रखना। सभी इसके (मोर्चे के) लक्ष्य को एक दल स्थापित करने की समस्याओं से बचने के उपाय के अतिरिक्त अन्य दलों—विशेषतया कांग्रेस—को तोड़ने की इच्छा का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी में रहकर भी मोर्चे का सदस्य बन सकता है। न दोहरी सदस्यता का मामला बनता है, न दल बदलने का आरोप लगता है। दल बदलने में माहिर एक प्रख्यात बुजुर्ग नेता के अनुसार मोर्चे का वर्तमान स्वरूप दलबदल विरोधी कानून की सीमा लांघने और इसके दायरे से दूर रहने के लिए ही किया गया है। "संभावित ग्राहकों के लिए एक दुकान खाल दी गयी है। खासकर इस विचार से कि किसी भी पार्टी का जो भी सदस्य आये, वह अंत में उनका ही हो जाये।" यही विचार शायद सभी दलों के नेताओं के लिए चिन्ता का कारण बन गया है। गुटों में निगरानी का काम आरंभ हो जाना सहज स्वाभाविक है, यद्यपि सभी दल सत्ताधारी और विपक्ष पर किसी तरह की आंच न आने का जोरदार दावा कर रहे हैं।

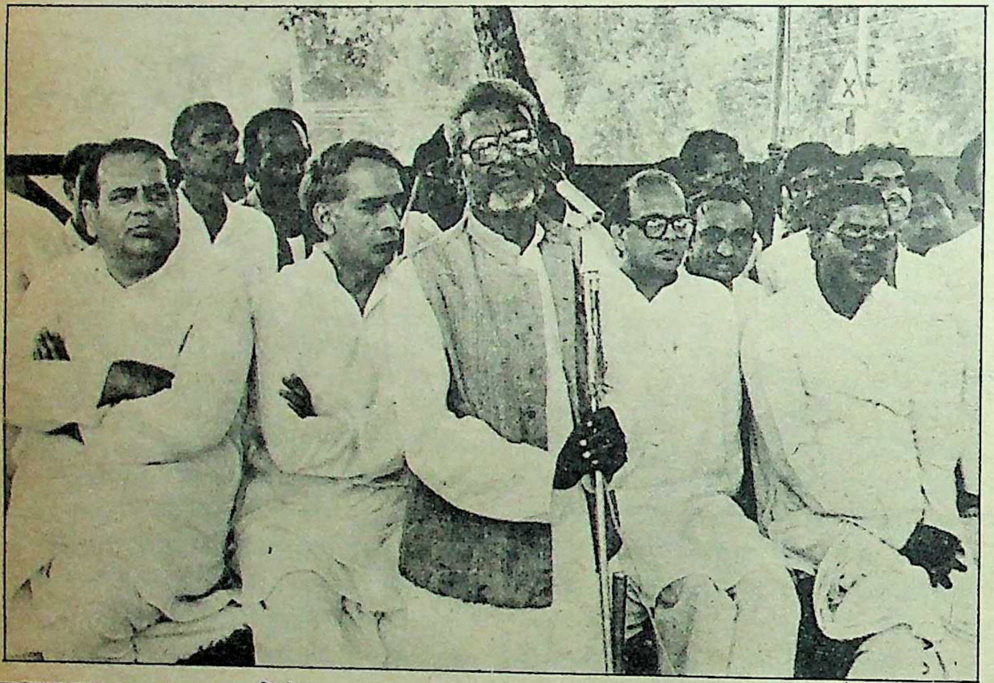

दलबदल कानून हम पर लागू नहीं होता : एक गांव की सभा में 'मोर्चा' के संयोजक रामधन भाषण देते हुए, साथ में वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू व विद्याचरण शुक्ल

वी०पी० सिंह की रणनीति : ऊपर चर्चित अनुभवी नेता के अनुसार, "मोर्चे के कारण विपक्ष से कहीं अधिक खतरा कांग्रेस को है। एक तो असंतुष्टों की गिनती भी वहां अधिक है, दूसरे वी०पी० सिंह आरंभ से ही कांग्रेसियों को ही अधिक संबोधित करते दिखायी पड़ रहे हैं।" उनके लक्ष्य की पुष्टि इसी बात से होती है कि न तो उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का कोई विशेष प्रयास किया है, न ही विपक्ष को तोड़ने की चेष्टा। लगभग सारा परिश्रम कांग्रेस के ही भीतर तोड़-फोड़ करने में लगाया जा रहा है। दरअसल वी०पी० सिंह कांग्रेस में तोड़-फोड़ इसलिए नहीं चाहते हैं कि वह कांग्रेस का विकल्प बने, वरन इसलिए कि कांग्रेस के भीतर या कांग्रेसियों के साथ वह राजीव सरकार का विकल्प बना सकें। "कांग्रेसी" चरित्र को देखते हुए, सत्ता के प्रति उसके सम्मोहन को जानते हुए और यह समझते हुए कि जिस दिन भी कांग्रेसियों को यह जान पड़ा कि राजीव गांधी उनके लिए लाभ का नहीं, बल्कि घाटे का सौदा हो गये हैं, वह तुरंत उनसे पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसे में वी०पी० सिंह की इस चाल की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। किंतु अनेक अनुभवी राजनीतिज्ञों को डर है कि अंततः यह अधकचरी चालाकी न सिद्ध हो जाये, विशेषकर इसलिए कि स्वयं कांग्रेस इन चालों के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं है और डटकर मुकाबला करने को तत्पर है। महासचिव केदारनाथ सिंह वी०पी० सिंह की बाढ़ को रोकने के लिए संसद के अगले सत्र में दलबदल विरोधी कानून में संशोधन लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही वह संबंधित अधिकारियों के पास जाकर वी०पी० सिंह व उनके अन्य साथियों को वर्तमान कानून के तहत दलबदलू घोषित कराने पर उतारू लगते हैं। श्री सिंह के सहयोगी महासचिव गुलाम नबी आजाद तो त्यागपत्र की मांग रख रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार मोर्चे की स्थापना कर वी०पी० सिंह ने दल बदल लिया है।

स्वाभाविक है कि वी०पी० सिंह ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बाध्य हों। वह भी अकारण कीचड़ उछालनेवालों को बख्शने को तैयार नहीं। संसदीय सीट से निकालने या त्यागपत्र की मांग करने वालों के संबंध में 'माया' से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "कौन होते हैं यह तदर्थ नामजद अधिकारी जो हम जैसे निर्वाचित सांसदों से त्यागपत्र की मांग करें। यदि वायदा न पूरा करने पर त्यागपत्र मांगा जा सकता है, तो सत्ताधारी दल के सभी संसद सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय जारी किये गये घोषणापत्र के वायदों को उन्होंने कतई नहीं निभाया है।"

विश्वनाथ प्रताप सिंह यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वह अथवा जनमोर्चा दिशाहीन या भ्रामक है। "हम प्रारंभ से ही कुछ विशिष्ट मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और उन मुद्दों पर *हम अडिग हैं।*" सिंह को नजदीक से जानने वाले एक पर्यवेक्षक के अनुसार वी०पी० सिंह ने कच्ची गोलिया नहीं खेली हैं। उन्होंने व्यापक परिणामों को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ प्रत्येक कदम उठाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दी गयी चुनौती के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरे ऐसे कांग्रेसी हैं, जिन्होंने समस्त कांग्रेस संगठन को चुनौती दी है। श्रीमती गांधी की सफलता के पीछे उनके परिवार के नाम का भी विशेष हाथ था, जिससे वी०पी० सिंह निश्चय ही वंचित हैं। किंतु जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की मांग को आधार मानकर, जिसके तहत अन्त में जनता पार्टी का जन्म हुआ था, जो अभियान वी०पी० सिंह ने चलाया है—उसका एक आंधी में परिवर्तित हो जाना न असंभव होगा न आश्चर्यजनक। जनमोर्चा केवल एक राष्ट्रीय मोर्चे के गठन का प्रारंभिक मंच है। यह बात वी०पी० सिंह भी उतना ही जानते-समझते हैं, जितना कि अन्य सभी राजनीतिक दल।

सभी दल चिंतित : यही जानना-समझना एक ओर सभी दलों की रातों की नींद खराब करने के लिए पर्याप्त है, तो दूसरी ओर वी०पी० सिंह के साथ हाथ मिलाने को बाध्य भी करता है। कांग्रेस शिविर चाहे इसे विपक्ष की मौकापरस्ती माने, जिसके तहत विपक्ष अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अथवा वी०पी० सिंह पर दूसरों के बलबूते आगे बढ़ना समझे। इसमें संदेह नहीं कि आज सभी दलों की हालत सांप-छछूंदर की-सी है। वे आज सिंह या जनमोर्चा की न तो उपेक्षा कर सकते हैं, न ही उसके बहुत नजदीक बिना अपना अस्तित्व खोये जा सकते हैं। यही कारण है कि कई दल अब अपना अलग अभियान भी चलाने के लिए बाध्य हो गये हैं। यह दूसरी बात है कि इसके लिए उठाये तमाम मुद्दे मोर्चे से ही उधार लिये दिखायी पड़ते हैं।

लोकदल (अ) के सुब्रह्मण्यम स्वामी के अनुसार मोर्चे की सफलता का सर्वाधिक प्रभाव जनता पार्टी और भाजपा पर पड़ेगा। कुछ वरिष्ठ जनता नेता-कर्नाटक के रामकृष्ण हेगड़े और उड़ीसा के बीजू पटनायक खुले आम वी०पी० सिंह के साथ

ह ईंट का
। वह भी
को तैयार
ागपत्र की
बातचीत
यह तदर्थ
सांसदों से
करने पर
री दल के
ा चाहिए,
पणापत्र के
है।''
को तैयार
ाहीन या
मुद्दों को
डिग हैं।''
ीक्षक के
ही खेली
रखते हुए
महत्वपूर्ण
दी गयी
दूसरे ऐसे
गठन को
ा के पीछे
हाथ था,
हैं। किंतु
मांग को
नता पार्टी
० सिंह ने
र्वतित हो
जनमोर्चा
भिक मंच
ही जानते-
तिक दल।
झना एक
करने के
० सिंह के
है। कांग्रेस
ती माने,
र रहा है,
बूते आगे
सभी दलों
न सिंह या
ही उसके
जा सकते
ना अलग
ये हैं। यह
मुद्दे मोर्चे

वामी के
क प्रभाव
छ वरिष्ठ
र उड़ीसा
ह के साथ

निलॉन्स टूटी-फ्रूटी मुफ्त!*

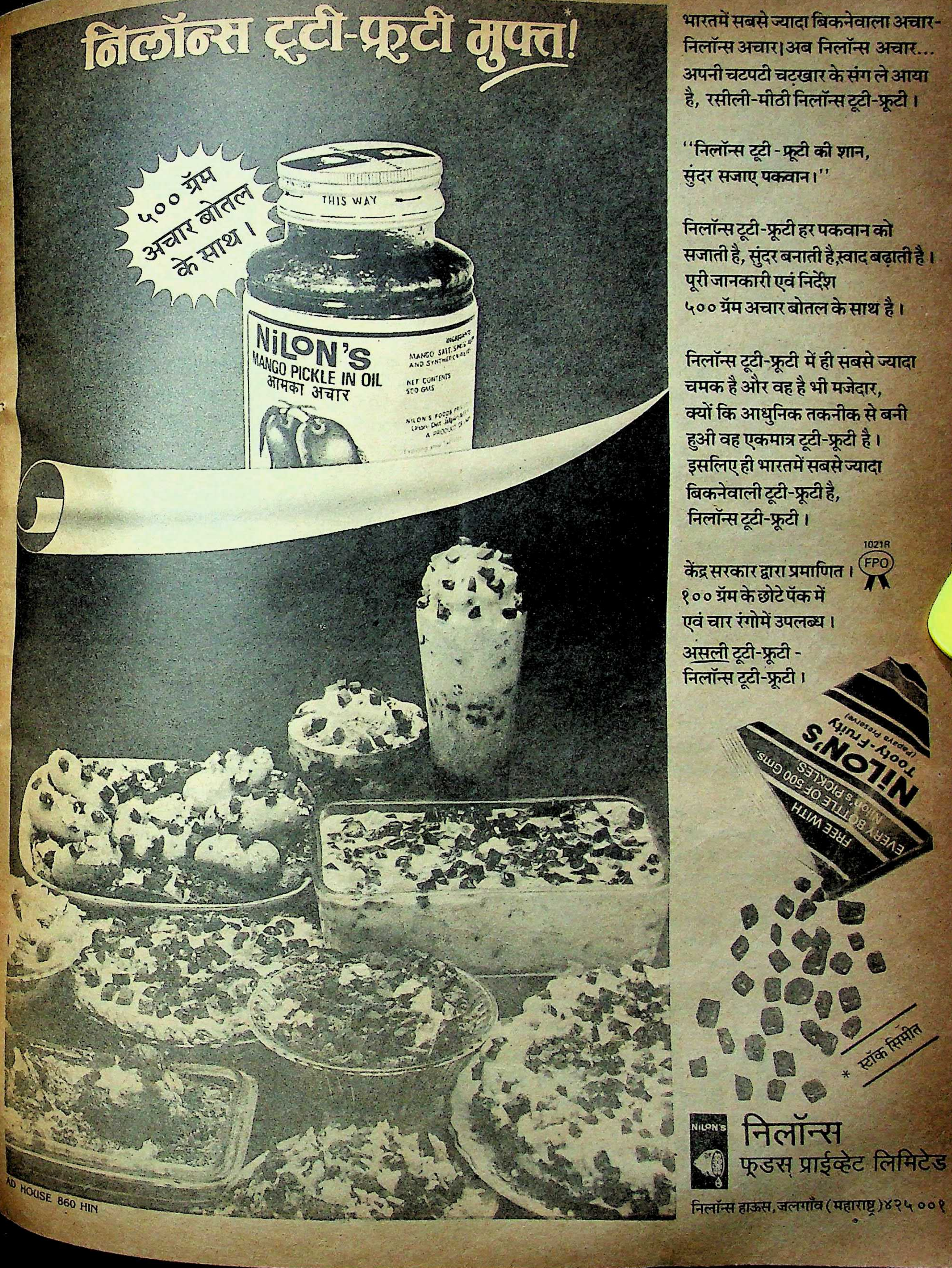
५०० ग्रॅम अचार बोतल के साथ।
THIS WAY
NiLON'S
MANGO PICKLE IN OIL
आमका अचार
NiLON'S
Tooty-Fruity
(Papaya Preserve)
FREE WITH
EVERY BOTTLE OF 500 Gms.
NiLON'S PICKLES

भारतमें सबसे ज्यादा बिकनेवाला अचार-
निलॉन्स अचार। अब निलॉन्स अचार...
अपनी चटपटी चटखार के संग ले आया
है, रसीली-मीठी निलॉन्स टूटी-फ्रूटी।

''निलॉन्स टूटी - फ्रूटी की शान,
सुंदर सजाए पकवान।''

निलॉन्स टूटी-फ्रूटी हर पकवान को
सजाती है, सुंदर बनाती है,स्वाद बढ़ाती है।
पूरी जानकारी एवं निर्देश
५०० ग्रॅम अचार बोतल के साथ है।

निलॉन्स टूटी-फ्रूटी में ही सबसे ज्यादा
चमक है और वह है भी मजेदार,
क्यों कि आधुनिक तकनीक से बनी
हुई वह एकमात्र टूटी-फ्रूटी है।
इसलिए ही भारतमें सबसे ज्यादा
बिकनेवाली टूटी-फ्रूटी है,
निलॉन्स टूटी-फ्रूटी।

केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित। 1021R FPO
१०० ग्रॅम के छोटे पॅक में
एवं चार रंगोमें उपलब्ध।

असली टूटी-फ्रूटी -
निलॉन्स टूटी-फ्रूटी।

* स्टॉक सिमीत

NiLON'S
निलॉन्स
फूडस प्राईव्हेट लिमिटेड

निलॉन्स हाऊस, जलगाँव (महाराष्ट्र) ४२५ ००१

AD HOUSE 860 HIN

केदार नाथ सिंह

कांग्रेस-इ महासचिव केदारनाथ सिंह वी०पी० सिंह की बाढ़ को रोकने के लिए संसद के अगले सत्र में दलबल विरोधी कानून में संशोधन लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही वह संबंधित अधिकारियों के पास जाकर वी०पी० सिंह व उनके अन्य साथियों को वर्तमान कानून के तहत दलबल घोषित कराने पर उतारू लगते हैं।

यशवंत सिंहा

जनता पार्टी के महासचिव यशवंत सिंहा ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वरूप को स्वीकार करने में मोर्चे को किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्यों और कार्यक्रमों के प्रति मोर्चे की झिझक को समझ पाने में मैं असमर्थ हूं।

हैं। हांलाकि पटनायक के लिए कहा जाता है कि वह वी०पी० सिंह के साथ इसलिए हैं, क्योंकि उनका वरदहस्त जे०बी० पटनायक की कांग्रेसी सरकार को गिराने के लिये आवश्यक है। हेगड़े-चन्द्रशेखर की अपनी-अपनी गोटी लाल करने की राजनीति, हेगड़े को सिंह के खेमे के नजदीक ले जाने का कारण मानी जा रही है। फिर भी यशवन्त सिन्हा इसे खतरे की घंटी मानने को तैयार नहीं हैं।

भाजपा जनमोर्चा और विशेषकर वामपंथ की चुनौती को कितना महत्वपूर्ण समझ रही है, यह इससे पता चलता है कि एक नवंबर से ही उन्होंने एक देशव्यापी राजीव हटाओ अभियान का ऐलान कर दिया है। किंतु उद्देश्य स्पष्ट है। एक ओर वामपंथ को नीचा दिखाना है, दूसरी ओर अपनी स्थिति इतनी मजबूत बनानी है कि वी०पी० सिंह बरबस उनका ही हाथ थामें—वामपंथ का नहीं। वामपंथ से भाजपा के वर्तमान घमासान युद्ध का मुख्य कारण यही है कि दोनों दल वी०पी० सिंह के साथ जुटकर उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहते हैं। दोनों ही दलों का प्रभाव फिलहाल क्षेत्रीय तथा सीमित है और उनमें जनमोर्चा के साथ जुड़कर राष्ट्रीय प्रभाव हासिल करने की ही सारी होड़ है। इसलिए वामपंथ भी समर्थन हासिल करने में पीछे नहीं है। एक दिसंबर से वह भी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने पर उतारू है। यद्यपि उसका नारा सांप्रदायिकता के खिलाफ है, जिसका सीधा निशाना है, भाजपा।

यद्यपि लोकदल मोर्चे के प्रभाव से अछूता रहने का दावा करता है, किंतु प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लोकदल (अ) के नेता अजीत सिंह, वी०पी० सिंह के साथ भरत मिलाप करने के काफी इच्छुक हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत हो भी चुकी है। अतः सुब्रह्मण्यम स्वामी के इस दावे में कि लोकदल (अ) का अपना विशिष्ट वोट बैंक है, जिसमें वी०पी० सिंह और जनमोर्चा का प्रवेश और प्रभाव असंभव है, कुछ खोखला दिखायी देता है। निश्चय ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोकदल (अ) का गढ़ है, किंतु उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की लगभग ३५ सीटों पर हरिजनों और आदिवासियों का जोर है और इस गुट के रामधन के साथ हो जाने की पूरी संभावना है।

लोकदल (ब) की स्थिति जनता पार्टी से मिलती-जुलती है। यदि अध्यक्ष बहुगुणा का वामपंथी झुकाव हाथ रोकने को बाध्य किये है, तो हरियाणा विजेता देवीलाल का भाजपा संपर्क उन्हें जनमोर्चा को सहयोग और बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करता है। मोर्चे का किसानों के प्रति रुख और नीतियां दोनों को सहज ही हमसफर बना देती हैं।

ज्यों-ज्यों समय बीतेगा, त्यों-त्यों मोर्चा अधिक संगठित, सुव्यवस्थित और सफल होगा। मोर्चे के एक प्रवक्ता के अनुसार सदस्यता के संकल्प-पत्र की मांग में बेहिसाब बाढ़ आ रही है। वैसे भी वर्तमान आन्दोलन को स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई मानने वाले मोर्चे के नेताओं ने शीघ्र ही एक करोड़ संकल्प-पत्र भरवाने का ऐलान कर दिया है। परिणाम साफ जाहिर है। लहर के तूफान में परिवर्तित हो जाने में देर भले हो, संदेह नहीं।

गुलाम नबी आजाद

क्योंकि मोर्चा संभालनेवाले सभी नेता पुराने, असंतुष्ट कांग्रेसी हैं। अतः कांग्रेस-इ महासचिव गुलाम नबी आजाद द्वारा मोर्चा को जंक (कबाड़), वी०पी० सिंह को ढुलमुल विचारोंवाला और संयोजक रामधन को 'गिरगिट' करार देना कांग्रेस के रोष-प्रदर्शन का एक अनूठा नमूना है।

मोर्चा अपने जन संपर्क कार्यक्रम में दिनो-दिन तीव्र गति से वृद्धि करता जा रहा है। विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो जैसे इसका सैलाब-सा आता जा रहा है। हो सकता है जैसा कि गुलाम नबी आजाद कहते हैं, "भीड़ से वोटों का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता," सही हो क्योंकि पश्चिम बंगाल का उदाहरण और अनुभव उनके सामने है। किंतु जनसभाओं और जनसंपर्कों द्वारा कांग्रेसी सरकार के प्रति जो संदेह के बीज बो दिये गये हैं, जिनके कारण स्वयं प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है, उसका निवारण केवल व्यापक जनसंपर्क से ही संभव है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस संगठन इसके प्रति उदासीन है और इस दिशा में फिलहाल कोई ऐसा कारगर कदम उठाता दिखायी नहीं देता। यह अंततः सरकार और पार्टी दोनों के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। निर्णायक घड़ी में वक्तव्यों और जनसंचार माध्यमों से काम चल पायेगा, ऐसी आशा करना अमावस में चांद देखने के समान होगा। बेखबरी के इस आलम में कांग्रेस के लिए जनमोर्चा जिसे वह 'जंक' मोर्चा करार दे रहे हैं, ऐसा जंग मोर्चा सिद्ध हो सकता है जिसमें शिकस्त से उसे कोई नहीं बचा सकेगा।

—रंजना कक्कड़

छाया : गिरीश श्रीवास्तव, रंजन बसु

एक चमत्कारी किसान नेता

लोग चाहे उनको सनकी कहें, चाहे वह पागलखाने में रहे हों, चाहे वह अनपढ़ हों, लेकिन यह तथ्य है कि जिस तूफानी गति से वह किसानों में लोकप्रिय हुए हैं, उससे देश के दिग्गज राजनेता चकित और भयभीत हो गये हैं। देश का हर दल, हर नेता उनके समर्थन के लिए तरसता है, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालते। वह मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को भरी सभा में बेआबरू कर चुके हैं, राजीव गांधी को ललकार चुके हैं और वी०पी० सिंह को खरी-खरी सुना चुके हैं। उनकी एक आवाज पर लाखों किसान एकत्र हो सकते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। भारतीय किसान राजनीति के इस नये चमत्कार का नाम है—महेन्द्र सिंह टिकैत। यह टिकैत कौन हैं? यह किसानों के मसीहा कैसे बन गये? किन गतिविधियों के कारण इन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है। बेताज के बादशाह महेन्द्र सिंह टिकैत और उनके संगठन की अंदरूनी कहानी बयान कर रहे हैं अजय कुमार और सुरेश द्विवेदी

महेन्द्र सिंह टिकैत

राजधानी दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुश्तैनी जाट खापों से भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसी गैर-राजनीतिक हस्ती—महेन्द्र सिंह टिकैत—का उदय हो रहा है, जिसने कानून की सारी किताबों और प्रशासन को अपनी जेब में रखकर सवा करोड़ से अधिक आबादीवाले २५ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिर्फ एक वर्ष में ही बेताज बादशाहत कायम कर ली है। उनके एक इशारे पर इस पूरे क्षेत्र में 'रणसिंघा' बजने लगते हैं और २४ घंटे से भी कम समय में लाखों किसान अपने हथियारों के साथ एकत्र हो जाते हैं। उनकी अपनी सेना है, अपनी अदालत व जेल है और जो वह बोल देते हैं, वह कानून बन जाता है। (देखिए बाक्स) दर्जा सात फेल (और रिपोर्टों के अनुसार दो बार आगरा पागलखाने से इलाज करवा चुके) टिकैत की ताकत का आलम यह है कि वह मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की लाखों किसानों की सभा में इज्जत उतार चुके हैं, पिछले छह महीनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान लगान व बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की मजाल

किसान यूनियन
अराजनैतिक
शहीद किसान अमर रहे....
भारतीय
अत्याचार

क्रांति की मशाल : टिकैत अमरज्योति में देशी घी डालते हुए

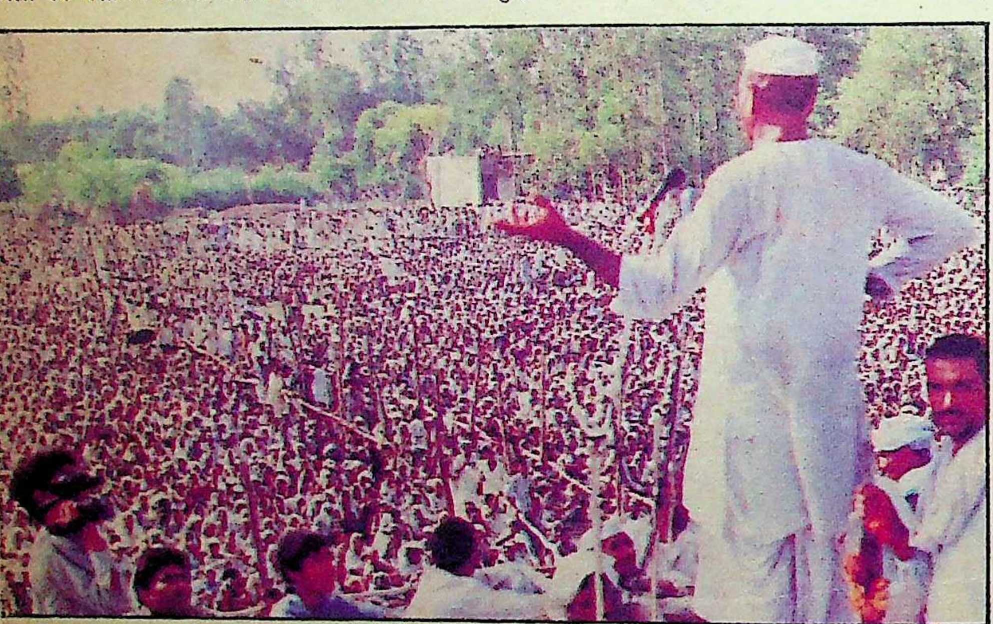

जनाधार का आलम : टिकैत एक सभा में बोलते हुए

आतंक भी, लोकप्रिय भी : टिकैत और उनका कमांडोदस्ता

क्या जो किसानों को पानी और बिजली देने में हीला-हवाली कर सके। मजाक में यहां तक कहा जाने लगा है कि उसके इलाके का सरकारी महकमा—कमिश्नर से लेकर थानेदार तक—वेतन तो सरकारी खजाने से पाता है, लेकिन हुकुम टिकैत से लेता है।

मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी राजेंद्र सिंह यादव कहते हैं, "किसानों द्वारा लगान और बिजली का मूल्य अदा न करने से सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। जिन किसानों ने बैंक या सरकार से ऋण ले रखा है, उसकी भी अदायगी नहीं हो रही है। अब तो यहां के किसान यह तक मांग करने लगे हैं कि उन्हें बीज और खाद मुफ्त मिलनी चाहिए।"

एक साल पहले तक टिकैत का नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कांग्रेसी नेताओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक सभी उनकी नज़रे-इनायत के लिए बेताब हैं, जबकि वह एक सिरे से सब पर चोट कर रहे हैं। राजनीति से जुड़े सभी लोगों को दुत्कार रहे हैं, चाहे वह राजीव गांधी व वीर बहादुर सिंह हों या विश्वनाथ प्रताप सिंह व देवीलाल। लेकिन मजा यह है कि सभी उनकी लताड़ खाकर भी चाहते हैं कि टिकैत उनके बीच में आयें। पर टिकैत कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि कोई राजनेता उनके मंच पर आये। अब टिकैत दिल्ली को ललकार रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगले वर्ष वह दिल्ली की सड़कों पर ४० लाख किसानों का प्रदर्शन करेंगे। केन्द्र सरकार सहमी हुई है, क्योंकि पिछले अनुभवों से वह जानती है कि इतने किसानों को एकत्र कर लेना टिकैत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।

कौन हैं, महेन्द्र सिंह टिकैत ? : मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र का सिसौली कस्बा टिकैत की बेताज बादशाहत की राजधानी है। शहर से ३५ किलोमीटर दूर २० हजार की आबादीवाले सिसौली गांव को टाउन एरिया का दर्जा प्राप्त है। टिकैत की असली ताकत है, भारतीय किसान यूनियन, जिसका गठन जाटों के विभिन्न गोत्रों के किसानों को संगठित करने के लिए किया गया था। इन गोत्रों को 'खाप' कहते हैं। पूरे देश में जाटों की ३६५ खापें हैं। सबसे बड़ी खाप 'देश खाप' तथा सबसे छोटी 'नैन खाप' है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में १८ बड़ी खापें हैं। स्वभाव से अक्खड़, किंतु खरी बात बोलनेवाले महेंद्र सिंह टिकैत ८४ गांवोंवाली बालियान खाप के चौधरी (मुखिया) हैं। खाप का चौधरी वंशानुगत होता है, यानी बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता अपनी खाप का चौधरी बनता है। इसके लिए समृद्धिशाली या पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी कुछ ऐसी ही परंपरा जुड़ी हुई है।

चौधरी चहोल सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह टिकैत को 'बालियान खाप' के चौधरी का पद मिला था। वर्ष १९३५ के आसपास की बात है। उस समय चहोल सिंह की माली हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी। तब वह अपनी पत्नी

मुख्तियारी को साथ लेकर पास के एक गांव हरसौली में जा बसे थे। नियमानुसार जब कोई चौधरी अपना पैतृक गांव छोड़ देता है, तो उसकी चौधराहट भी समाप्त हो जाती है। इसी बात को लेकर पंचायत हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि चूंकि चहोल सिंह पद संभालने में अक्षम हैं, इसलिए यह पद हरसौली गांव के किसी बालियान जाट को दे दिया जाये, लेकिन पंचायत के इस सुझाव से हरसौली गांववाले सहमत नहीं हुए। तब यह निर्णय लिया गया कि सब लोग मिलकर चहोल सिंह की मदद करें, जिससे चौधरी पद की गरिमा बरकरार रहे। इसी के बाद बालियान खाप के लोगों ने ४० बीघे खेत तथा सिसौली में गिरे-पड़े मकान को बनवाने के लिए चंदा एकत्र कर चहोल सिंह को सिसौली में पुनर्स्थापित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद टिकैत को विरासत में मिली यही 'चौधराहट' उनकी ताकत का आधार बन गयी और इसी के बल पर वह किसान यूनियन पंचायत के सर्वेसर्वा बन सके।

किसान यूनियन और टिकैत : उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन की नींव वर्ष १९७८ में तब पड़ी थी, जब मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। उस समय चरण सिंह के इशारे पर ही गुड़गांव (हरियाणा) के मुनेश्वर गांव निवासी राव हरलाल तथा रोहतक के कांधला ग्रामवासी अवकाशप्राप्त रिसालदार बलवीर सिंह ने यूनियन का गठन १३ अगस्त, १९७८ को किया था। इस पंजीकृत यूनियन (संख्या ३१४७) को गैरराजनीतिक करार देते हुए तब यूनियन का एक ही उद्देश्य रखा गया था, "किसानों के नाम पर जाटों को संगठितं करो।" इसी किसान यूनियन ने चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस २३ दिसंबर, १९७८ को दिल्ली में बहुत बड़ी किसान रैली आयोजित की थी, लेकिन १९८० और १९८४ के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की पार्टी की जबरदस्त पराजय के बाद किसान यूनियन की गतिविधियां ठंडी पड़ गयी। वर्ष १९८६ में जब चौधरी चरण सिंह बिस्तर से लग गये, तो उनका विकल्प ढूंढने के लिए यूनियन के पुराने पदाधिकारी सक्रिय हो उठे और इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में यूनियन ने पांव पसारने शुरू कर दिये।

यूनियन का सक्रिय पदार्पण इन इलाकों में तब हुआ, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त, १९८६ में किसानों को आपूर्ति की जानेवाली विद्युत दर साढ़े बाईस रुपए प्रति हार्सपावर से बढ़ाकर ३० रुपए कर दी। किसान यह वृद्धि स्वीकार कर लेते बशर्ते उन्हें नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति होती रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम किसान सरकार के इस रवैये से काफी नाराज था। यूनियन के लिए यह एक अच्छा मौका था। उसके राष्ट्रीय महासचिव कांधला निवासी बलवीर सिंह के आह्वान पर १७ अक्तूबर, १९८६ को सिसौली में एक किसान सम्मेलन हुआ। यद्यपि इस सम्मेलन में किसानों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी, किन्तु वहां किसानों की

नेतृत्व पर भरोसा : टिकैत अपने दलबल के साथ

किसान क्रांति की रणनीति : टिकैत एक जुलूस में

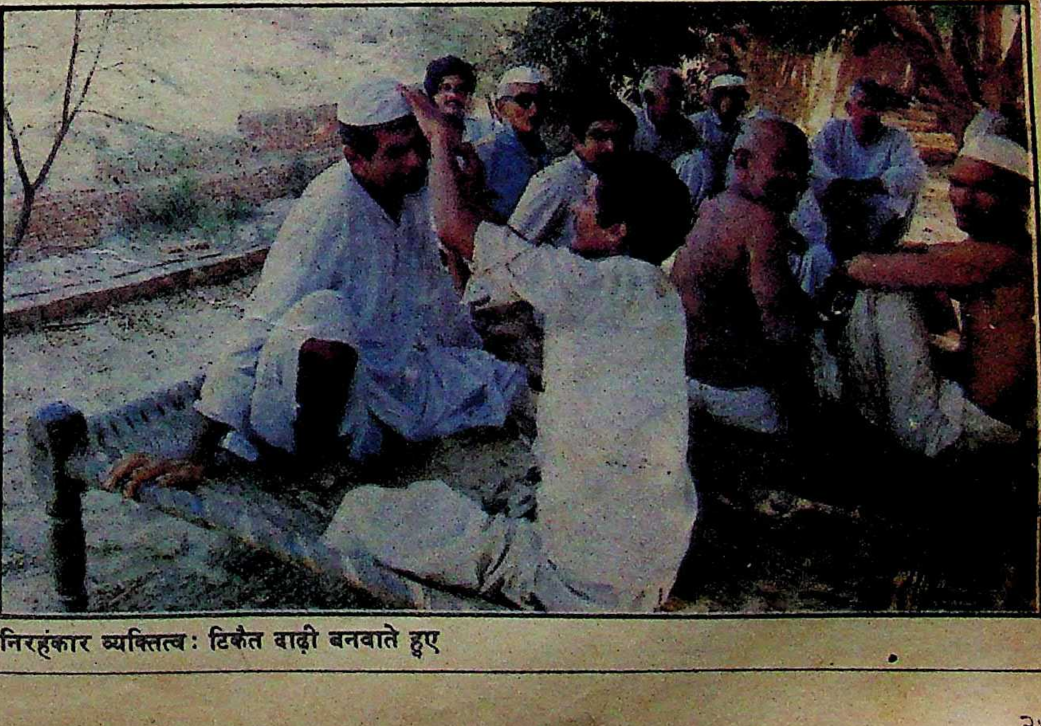

निरहंकार व्यक्तित्व : टिकैत दाढ़ी बनवाते हुए

बुनियादी समस्याएं—खाद, पानी, बिजली और सरकारी ऋण जैसे मामले उठाकर किसानों को आन्दोलित करने की रूप रेखा तैयार की गयी। उसी दिन वहां यूनियन की एक क्षेत्रीय शाखा का भी गठन कर दिया गया।

सिसौली जो अब भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय बन चुका है, तब क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया गया था। उस क्षेत्रीय शाखा में सेना के अवकाशप्राप्त हवलदार आशाराम (सिसौली निवासी) को अध्यक्ष तथा महेन्द्र सिंह टिकैत को क्षेत्रीय सचिव का पद दिया गया था। यूनियन का खर्च चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को प्रति बीघा एक रुपया और एक किलो अनाज की दर से चंदे का प्रावधान किया गया। उस समय सिसौली में किसान सम्मेलन आयोजित करने के पीछे बलवीर सिंह का एक उद्देश्य यह भी था कि सिसौली में अन्य ३६ जातियों के चौधरी भी रहते हैं। इन गैरजाट चौधरियों के जरिए किसानों को संगठित किया जा सकता था।

टिकैत का उदय: नवम्बर, १९८६ में महेन्द्र सिंह के समधी तथा देशखाप के चौधरी, बड़ौत निवासी सुखवीर सिंह ने बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में करीब एक हजार किसानों के साथ बड़ौत के विद्युतगृह का घेराव किया था। किसानों ने वहां धरना भी दिया था। धरने में टिकैत भी गये थे। इस धरने से परेशान बिजलीघर के अधिकारियों और पुलिस के अफसरों ने आश्वासन दिया था कि वे किसानों की समस्याएं सरकार तक पहुंचायेंगे। उस समय किसानों की एकजुटता और अधिकारियों की लाचारी ने टिकैत को काफी हद तक प्रभावित किया। यहीं से उनकी महत्वाकांक्षा जागी। सिसौली लौटते ही उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने का अपना इरादा पक्का कर लिया।

सिसौली से लगा हुआ भौराखुर्द गांव है। वहां के एक डाक्टर सत्येन्द्र सिंह की टिकैत से काफी पटती थी। सत्येन्द्र सिंह किसान यूनियन के मंडलीय संयोजक भी थे। सत्येन्द्र सिंह की सहायता से टिकैत ने एक ११ सूत्रीय मांग-पत्र तैयार किया। मांग-पत्र में किसानों की ही समस्याएं थीं, जिनके समाधान के लिए सरकार से मांग की गयी थी। मांग-पत्र तैयार होते ही टिकैत ने पंचायत बुलायी। उसमें सारी समस्याएं विस्तार से बतायीं, साथ ही ऐलान कर दिया कि इन मांगों को लेकर आसपास के गांवों के किसान २७ से ३० जनवरी, १९८७ तक शामली स्थित बिजलीघर पर धरना देंगे।

इस बीच टिकैत ने आसपास के तमाम गांवों में पंचायत कर किसानों से धरने में भाग लेने की अपील की। उसी के साथ संगठित रूप से यह भी प्रचार किया कि अगर धरना सफल हो गया, तो सरकार बिजली की बढ़ी दरें वापस ले लेगी। इस प्रचार का अच्छा असर हुआ। करीब २५ हजार किसानों ने तीन दिन तक लगातार शामली स्थित कर्मूखेड़ी पावर हाउस का घेराव किया।

जिला प्रशासन को इतने बड़े प्रदर्शन की स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी। सूचना पाकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने किसी तरह टिकैत के हाथ-पांव जोड़कर इस आश्वासन पर धरना समाप्त कराया कि स्थानीय स्तर पर किसानों की जो भी समस्याएं हैं, उनका तत्काल निराकरण कर दिया जायेगा। साथ ही बढ़ी विद्युत दर को वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार को लिखा जायेगा। टिकैत ने वहीं घोषणा कर दी थी कि अगर दो महीने के अन्दर बढ़ी दरें वापस नहीं ली गयीं, तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। इस धरने का एक असर यह हुआ कि जहां आसपास के गांवों में दो-दो दिन तक बिजली नहीं आती थी, अब दिन में एक-दो घंटे के लिए रोज आने लगी। जो सरकारी नलकूप महीनों से खराब पड़े थे, उनकी मरम्मत शुरू कर दी गयी।

उधर जिलाधिकारी राजेन्द्र सिंह यादव ने किसानों के इस आक्रामक रुख के बारे में प्रदेश सरकार को सूचित करते हुए यह संस्तुति की कि विद्युत की बढ़ी दरों से किसानों में काफी रोष है। उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाये। इस सूचना के बावजूद वीर बहादुर की

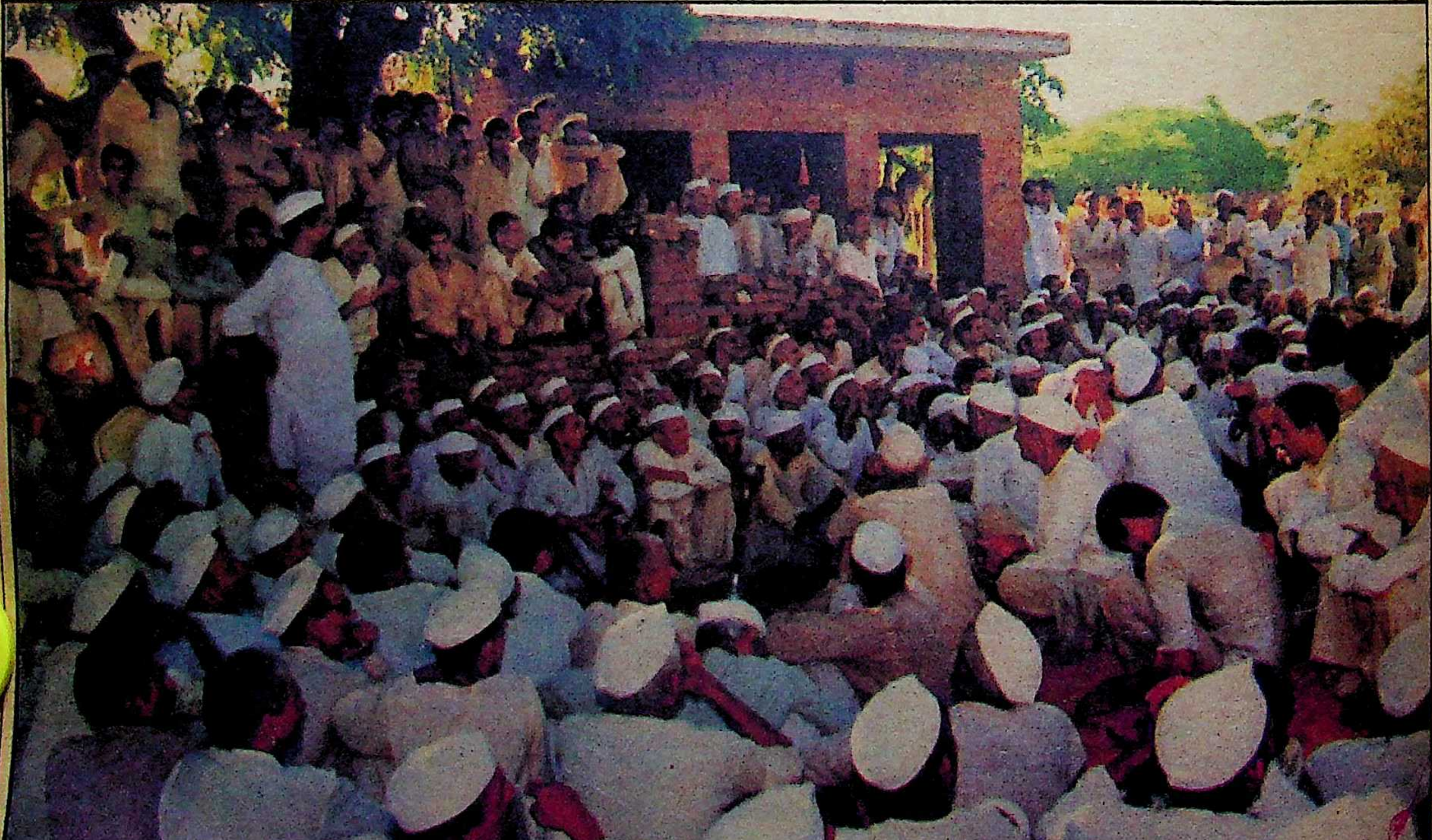

न्याय करने का अपना तरीका: टिकैत पंचायत में

सरकार ने इसे किसी मौसमी किसान नेता की कारगुजारी समझते हुए अपनी आंख बंद रखी।

सरकार की इसी अदूरदर्शिता का परिणाम पहली मार्च की घटना रही। दो माह का समय बीतते ही टिकैत ने ऐलान कर दिया और १ मार्च को पुनः पावर हाउस के घेराव के लिए एक लाख से भी ज्यादा किसान शामली पहुंच गये थे। पुलिस ने इस भीड़ को पावर हाउस की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की, तो संघर्ष हो गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आये। कर्मूखेड़ी पावर हाउस में आग लगा दी गयी। पुलिस की गोली से जब दो किसान जयपाल और अकबर मारे गये, तो उत्तेजित किसानों ने पी०ए०सी० के एक कमाण्डर आर०एस० यादव को पीट-पीटकर मार डाला।

इस घटना के नामजद किसानों को पकड़ने के लिए जब पुलिस गांवों में घुसी, तो वहां से किसानों ने पुलिस को खदेड़ दिया। इसी घटना के बाद महेन्द्र सिंह टिकैत 'हीरो' बन गये। पहली मार्च की वारदात के बाद सरकार की कान में जूं रेंगी। अगले दिन वीर बहादुर सिंह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने मंत्रिमंडल के तीन सहयोगियों—गोपीनाथ दीक्षित, नरेन्द्र सिंह और हुकुम सिंह को शामली भेजा। इन तीनों मंत्रियों ने स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद ११ में से १० मांगें स्वीकार करने की घोषणा कर दी तथा विद्युतदर संबंधी मांग मंत्रिमंडल से सलाह-मशवरा के बाद स्वीकार करने का आश्वासन दिया।

अपने बढ़ते रुतबे से जहां टिकैत मन-ही-मन खुश थे, वहीं किसानों को भी यह उम्मीद बंध गयी कि टिकैत ही सरकार को झुका सकते हैं। इस बीच १७ मार्च को टिकैत ने सिसौली में फिर एक सभा की। इसमें भी एक लाख से ज्यादा किसान थे। इसी सभा में घोषणा की गयी कि अगर ३१ मार्च तक सरकार ने बिजली की बढ़ी दरें वापस न लीं, तो पहली अप्रैल को फिर पावर हाउस का घेराव किया जायेगा और इस बार पांच लाख किसान धरना देंगे।

टिकैत की इस धमकी के बाद सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटी। २६ मार्च को ही वीर बहादुर सिंह ने घोषणा कर दी, "विद्युत की बढ़ी दरें वापस ली जा रही हैं। इससे प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष २६ करोड़ रुपए का घाटा होगा।" मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद भी टिकैत ने पहली अप्रैल को धरना आंदोलन वापस नहीं लिया। इस बारे में उनका कहना था, "लखनऊ या दिल्ली में बैठकर हमारे बारे में कोई भी निर्णय लेना हमें स्वीकार नहीं। समझौता अब तभी होगा जब मुख्यमंत्री किसानों के बीच आकर बात करेंगे।"

इस सब के बावजूद पहली अप्रैल को शामली में किसानों की जो रैली हुई, वह न केवल पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, वरन ऐतिहासिक भी थी। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर दिल्ली में हुई किसान रैली से भी ज्यादा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से पुलिस और पी०ए०सी० के जो आठ हजार जवान बुलाये गये थे, वह सब हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे। व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी 'किसान सेना' के जवानों ने संभाल रखी थी। रोचक तथ्य यह है कि भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी टिकैत द्वारा आयोजित किसी भी सभा या रैली में शामिल नहीं हुआ। इस बारे में टिकैत बताते हैं, "यूनियन के माध्यम से मैं किसानों को संगठित कर रहा हूं। ऐसा ही दायित्व मुझे सौंपा गया था। अब यूनियन के राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी यहां आयोजित किसानों की सभा या रैली में नहीं आता, इसमें मेरा दोष नहीं, बल्कि उनकी उदासीनता है।"

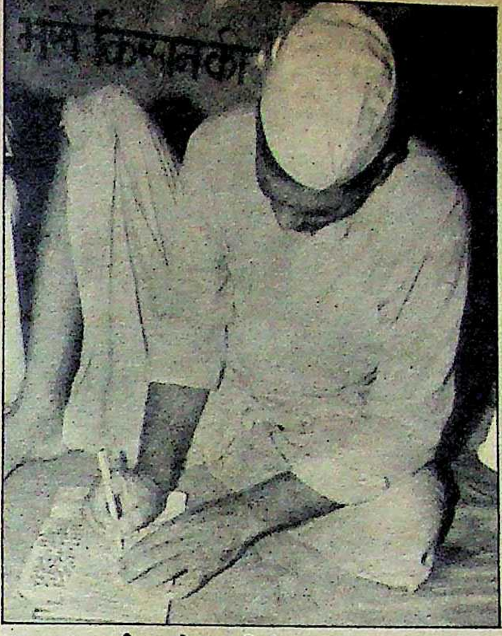
फरमान जारी करते हुए टिकैत

एक अप्रैल की रैली में ही महेंद्र सिंह टिकैत को यूनियन का प्रदेशीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उस ऐतिहासिक रैली के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जागरुकता खुलकर सामने आ गयी। गांव-गांव में यूनियन की इकाइयां गठित होने लगीं। अनेक गांवों में यूनियन की सभा कराने के लिए लोग टिकैत के पास आने लगे। अबतक टिकैत मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, बिजनौर, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं आदि जिलों में ५० से अधिक सभाओं का आयोजन और २५० से अधिक इकाइयां गठित कर चुके हैं। किसानों की एकजुटता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि छोटी-सी-छोटी सभा में भी एक लाख किसानों का एकत्र होने अब मामूली बात हो गयी है। भीड़ इकट्ठा करने के लिए न तो किसी संदेश की आवश्यकता पड़ती है, न किसी प्रचार की। 'रणसिंघा' बजते ही किसानों की भीड़ सभा-स्थल की ओर दौड़ पड़ती है। भारत जैसे देश में यह पहली बार हो रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी या नेता की रहनुमाई के बगैर लाखों किसान एक व्यक्ति की आवाज पर इकट्ठे हो रहे हैं। टिकैत कहते हैं, "किसान अब अपनी समस्याओं का निदान स्वयं करेगा। हमारी कोई मांग नहीं, जो हक बनता है, उसे हम लेकर रहेंगे।"

बगावत का बिगुल: टिकैत का रणसिंघा

छाया: आर०के० राजू

आंतक और विरोध: भारतीय किसान यूनियन को संगठित करने के लिए टिकैत ने प्रत्येक गांव में पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इन पंचायतों का मुख्यालय (सर्वोच्च पंचायत) टिकैत के गांव सिसौली में स्थापित किया। कानून व्यवस्था के लिए 'किसान सेना' गठित की, जिस पर अपराधियों की खोज, विरोधियों की गुप्तचरी और सम्मेलनों में शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी रहती है। उनकी कोशिश यही है कि उनके इलाके में उनकी मरजी के बिना परिंदा भी पर न मारने पाये। वह अपने इलाके में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना, शाहपुर, फुगाना, भौरांकलां और तितावी थाने की पुलिस टिकैत से राय-मशविरा किये बिना कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करती। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को टिकैत से बात करने के पहले उनके 'मूड' का पता करना पड़ता है। जिला प्रशासन ने उनके इस आतंक को ध्यान में रखकर यूनियन प्रभावित इलाकों में जाट अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया है। टिकैत ने नारा दिया है कि गांव के झगड़े गांव में ही निपटाये जायें—इससे पुलिस की अंधी कमाई पर अंकुश लग गया है। टिकैत के आतंक का आलम तो यह है कि इस समृद्ध क्षेत्र में रिश्वत देकर पुलिस एवं बिजली आदि विभागों के जो अफसर और कर्मचारी यहां तैनात हुए थे, वे अब मोटी रिश्वत देकर यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारबंद रक्षकों से घिरे टिकैत को अपने इलाके में सरकारी ही नहीं, बल्कि किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं है। वह नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में कोई दूसरी पार्टी किसानों के हित की बात करे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कौंसिल के सदस्य चंद्रबली सिंह अपने साथियों के साथ पार्टी के जेल भरो आंदोलन (७ से १३ दिसंबर) का प्रचार

साक्षात्कार —चौधरी सुखवीर सिंह

'टिकैत यूनियन के नाम पर तानाशाही कर रहा है'

बड़ौत (मेरठ) निवासी ९० वर्षीय सुखवीर सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की सबसे बड़ी 'देश खाप' के चौधरी हैं। चौधरी सुखवीर सिंह टिकैत के समधी हैं और इस समय उनके प्रमुख विरोधी भी।

यूनियन में वर्चस्व कायम करने के मसले पर दोनों एक दूसरे से विमुख हो गये हैं। खापों की बुनियाद पर टिकी भारतीय किसान यूनियन, इन चौधरियों के टकराव से दो फाड़ में बंट-सी गयी है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि दोनों के मध्य पारिवारिक स्तर पर भी मतभेद होने की चर्चाएं होने लगी हैं। अभी तक टिकैत का पलड़ा भारी है। एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने सुखवीर सिंह को चौधराहट की पदवी से हटवा कर 'देश खाप' का समर्थन हासिल किया है। प्रस्तुत हैं, सुखवीर सिंह से 'माया' की बातचीत के अंश:

माया: भारतीय किसान यूनियन का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया?

सुखवीर सिंह: वर्ष १९८३ में। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव हरलाल यहां आये थे। हम सबसे मिले। पंचायत हुई। किसानों को संगठित करने के लिए यूनियन का गठन किया गया।

माया: उस समय किसानों को संगठित क्यों नहीं किया जा सका?

सिंह: उस समय यूनियन की शाखाओं का गठन जिला और ब्लाक स्तर पर किया गया था। इसी वजह से आम किसान इससे जुड़ नहीं पाया था। इस कमी को ध्यान में रखकर ही खापों का सहारा लिया गया। खापों के माध्यम से हम किसानों को संगठित कर सकते थे। हमें उसमें सफलता मिली।

माया: महेन्द्र सिंह टिकैत की भागीदारी यूनियन में कब से है?

सिंह: अक्तूबर, १९८५ में जब संगठन को मजबूत करने के लिए खापों का सहारा लिया गया, तब से 'बालियान खाप' के चौधरी होने के नाते उसे भी शामिल किया गया था।

माया: क्या उस समय यूनियन ने टिकैत को कोई पद दिया था?

सिंह: पद की बात तो दूर, यूनियन के कागजी लिहाज से टिकैत न तो हमारी यूनियन का सदस्य है और न ही कोई पदाधिकारी.

माया: तो फिर टिकैत का वर्चस्व इतना कैसे बढ़ गया?

सिंह: किसानों के हित में बोलनेवालों को यूनियन ने कभी नही रोका। टिकैत ने यूनियन के नाम से किसानों की लड़ाई लड़ी। हम भी साथ थे। हम किसानों का हित चाहते हैं। वाह-वाही नहीं। टिकैत ने किसानों के नाम पर अपना नाम करने की सोची। अब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब वह किसानों की राजनीति चला रहा है।

माया: चर्चा है कि किसान यूनियन का नेता बनने के प्रश्न पर आपके और टिकैत के मतभेद बढ़े?

सिंह: मैंने कभी भी इस कारण टिकैत का विरोध नहीं किया। यह लालसा तो टिकैत की है। मैं तो शुरू से यूनियन में रहा, अब भी इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, जबकि टिकैत कुछ नहीं।

माया: फिर आप दोनों में मतभेद होने का क्या कारण है?

सिंह: मतभेद तो टिकैत ने पैदा किया। वह चाहता है कि किसानों की हित की बात करने में बस केवल उसी का एकाधिकार रहे। २७ मई को हमने बड़ौत में यूनियन की एक सभा की थी। टिकैत को भी बुलवाया था। वह इसलिए नहीं आया, क्योंकि यह सभा मैंने आयोजित की थी। यह तो सहयोग की बात नहीं हुई। समझ लीजिए इसी के बाद से हमारे और उसके मध्य मतभेद उपजा।

माया: मतभेद के और क्या कारण हैं?

सिंह: हमारी और उसकी कार्यप्रणाली और सोच में जमीन-आसमान का फर्क है। मैं किसान यूनियन चलाना चाहता हूं और टिकैत एक ट्रस्ट। अब वह यूनियन के नाम पर तानाशाही कर रहा है।

माया: टिकैत की तानाशाही के कुछ उदाहरण?

सिंह: एक बात हो तो बताऊं। आजकल वह (टिकैत) जो भी काम कर रहा है, उससे उसकी तानाशाही झलकती है। जिस यूनियन का वह सदस्य भी नहीं, आज उसी का अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किये बैठा है, जबकि

> ***माया: ऐसी चर्चा है कि आप अपनी पुत्रवधू (टिकैत की पुत्री) को वापस भेजने वाले हैं?***
>
> *सिंह: समाज में हमारी एक हैसियत है। 'देश खाप' की चौधराहट हमारे पास है। ऐसी ओछी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। यह अफवाह तो टिकैत ने फैला रखी है, ताकि वह अपने प्रति लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर ले तथा मुझे बदनाम करे।*

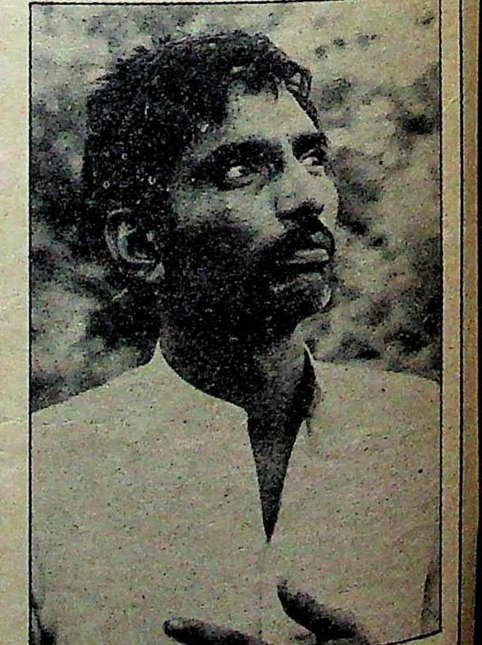

टिकैत के दामाद: सुरेन्द्र सिंह

वास्तव में राव हरलाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। टिकैत ने लाखों किसानों के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया। कुछ जायज-नाजायज मांगों को लेकर अब दिल्ली में (१७ अक्तूबर) प्रदर्शन करने जा रहा है। १३ अगस्त को जब यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिल्ली में किसानों की रैली आयोजित की, उस समय (टिकैत) यह कहकर कि हम शहरी गुण्डों के बीच नहीं जायेंगे, रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

(टिकैत ने यह प्रदर्शन स्थगित कर दिया था)

माया: सुना गया है कि टिकैत ने लोगों को सजा देने के लिए थाना, जेल और अदालत बना रखी है?

सिंह: सुना तो मैंने भी है। अब बताइये यह तानाशाही नहीं, तो क्या है। हम किसानों की लड़ाई महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के बल पर लड़ना चाहते हैं। हमें हमारा हक चाहिए, राज्य नहीं।

माया: आपको चौधरी पद से हटाने में क्या टिकैत का ही हाथ था?

सिंह: ऐसा ही समझ लीजिए। उसकी (टिकैत) मण्डली के ही महावीर सिंह ने २७ जुलाई को बावली ग्राम में हमारे खाप की पंचायत बुलायी थी। उसी दिन चौधरी की पदवी मेरे बड़े भाई देशपाल सिंह को देने की घोषणा की गयी। टिकैत तो मेरे घर में ही फूट पैदा कराने तक की नीचता पर उतर आया है।

माया: ऐसी चर्चा है कि आप अपनी पुत्रवधू (टिकैत की पुत्री) को वापस भेजने वाले हैं?

सिंह: समाज में हमारी एक हैसियत है। 'देश खाप' की चौधराहट हमारे पास है। ऐसी ओछी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। यह अफवाह तो टिकैत ने फैला रखी है, ताकि वह अपने प्रति लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर ले तथा मुझे बदनाम करे।

माया: टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नाम पर चंदा वसूल कर रहे हैं। उसका कोई हिसाब आपने मांगा?

सिंह: यह तो उसे खुद देना चाहिए। यूनियन के संविधान में ऐसा ही प्रावधान है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहेगी, हम टिकैत से हिसाब लेंगे।

माया: टिकैत के बारे में आपकी अपनी राय क्या है?

सिंह: वह ईमानदार है, लेकिन काफी चतुर भी है। मेरा तो यह मानना है कि टिकैत पागलपन का ढोंग करता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि यदि कोई बात (काम) वह गलत कर दे, तो बाद में यह कहकर बच सके कि उस समय मेरे दिमाग में गरमी चढ़ गयी थी।

—राजेन्द्र कुमार

करने के लिए जब भौंराखुर्द गांव में पोस्टर चिपकाने पहुंचे, तो टिकैत ने उन्हें पकड़ मंगाया। "मेरे इलाके में ये पोस्टर कैसे?" सवाल करते हुए टिकैत ने उन्हें दो झापड़ रसीद कर दिये और उनके हुकुम पर पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को शांति भंग की आशंका के आरोप में बंदी बनाकर जेल भेज दिया।

चंद्रबली सिंह ने 'माया' को बताया, 'प्रशासन भी उससे (टिकैत) भय खाता है। वह 'रणसिंघा' बजाकर थानों तक पर हमला बोल देता है। यही वजह है कि जब हम उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक के पास गये, तो उन्होंने भी अपनी बेबसी जाहिर कर दी।"

वस्तुतः ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग हैं, जब टिकैत ने थानों को घिरवा लिया था। जसोई गांव के अजब सिंह के पुत्र ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। टिकैत की किसान सेना ने अजब सिंह को पीटा, तो वह थाने पहुंच गया। पुलिस ने किसान यूनियन के दो कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। बस फिर क्या था, 'रणसिंघा बजा और किसान सेना ने तितावी थाने पर हमला बोल दिया। थानाध्यक्ष ने किसी प्रकार माफी मांग कर अपनी जान बचायी।

टिकैत का अपने इलाके में जैसे-जैसे आतंक बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उत्पीड़ित लोगों में उनका विरोध भी बढ़ रहा है। माण्डी गांव के प्रधान पंडित जगन्नाथ टिकैत की किसान यूनियन की इस कार्यपद्धति से काफी दुखी लगे। उनका कहना था, "जहां-जहां यूनियन की इकाई गठित हुई है, वहां प्रधान का कोई महत्व नहीं रह गया है। यूनियनवाले खुद पंचायत करते हैं। प्रधान को नहीं बुलाते। यही लोग जबरन चंदा वसूलते हैं। मेरे गांव में भी यही सब हो रहा है। हमने इसका विरोध किया, तो धमकियां मिलीं। मुझे तो अब यूनियन से अपनी जान का खतरा है।" वह बताते हैं, "यह यूनियन जाटों की है। क्षेत्र में इनका आतंक है। २१ अगस्त को जाटों ने दलपतपुर (थाना जानसठ) गांव में एक कानूनगो को इसलिए काटकर फेंक दिया कि उसने उनका कहा नहीं माना था। आज तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी।"

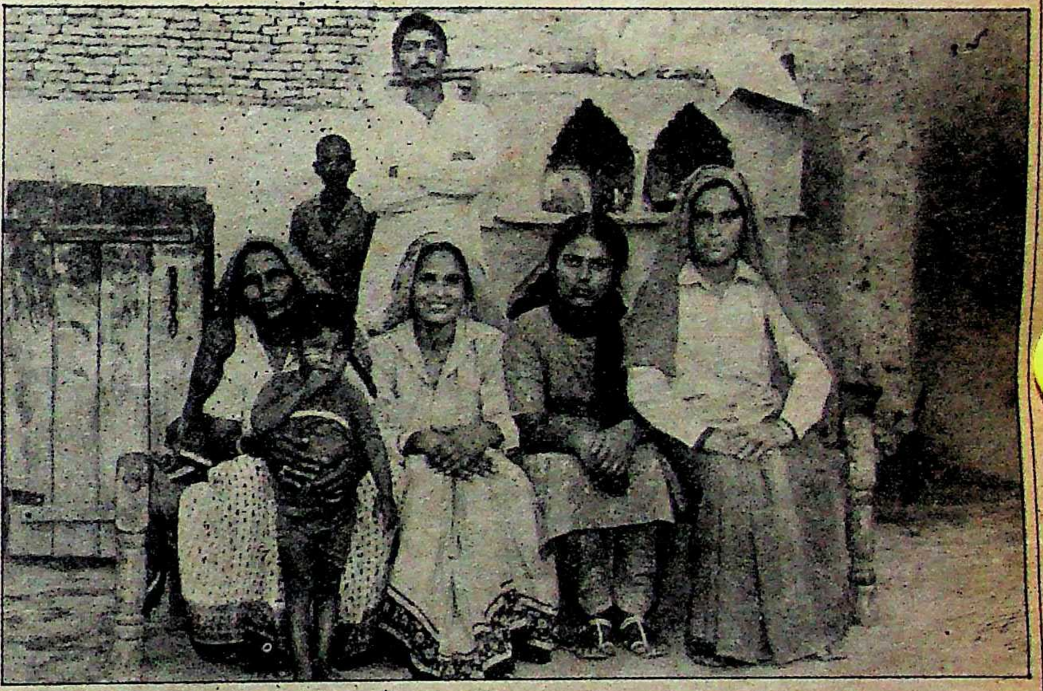

टिकैत का परिवार

किसान यूनियन के एक पदाधिकारी अनूप सिंह तो सीधे टिकैत की ईमानदारी पर चोट करते हैं। उनका आरोप है, "टिकैत यूनियन को अपनी जागीर मान बैठे हैं। यूनियन के चंदे का कोई भी हिसाब उन्होंने राष्ट्रीय समिति को नहीं दिया है। यूनियन ने उनके दौरे के लिए जो जीप दी थी, टिकैत ने उसका रजिस्ट्रेशन अपने भाई भोपाल सिंह के नाम से करा लिया है।"

अनूप सिंह का आरोप है कि टिकैत की इस घोषणा का कि किसान सरकार को अपना अनाज नहीं बेचेंगे, खुद टिकैत के ही आदमी फायदा उठा रहे हैं। ये लोग छोटे किसानों का गल्ला सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उसे यूनियन का झंडा लगे ट्रैक्टर से दिल्ली ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि इन ट्रैक्टरों को रास्ते में रोक कर चुंगी या सेल्स टैक्स मांगे।

सर्वखाप के भूतपूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह बताते हैं, "यूनियन का गठन खापों के माध्यम से जाटों को संगठित करने के लिए किया गया था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण टिकैत ने खापों में ही विघटन पैदा कर दिया है।"

उत्तर प्रदेश जनवादी नवजवान सभा के उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मजदूर नेता हैं। किसान यूनियन को वह जाटों का संगठन मानते हैं। वह कहते हैं, "टिकैत जाटवादी हैं। जहां-जहां जाटों की बात आयी, टिकैत वहां-वहां गये। लेकिन जहां गैरजाट के प्रति अन्याय हुआ, टिकैत खामोश रहे। सुरूरपुर में पुलिस की गोली से मारे गये दोनों छात्र जाट थे। एडवोकेट राजकुमार बालियान भी जाट थे। इन दोनों

क्या टिकैत फिर नीम से बंधेंगे ?

महेन्द्र सिंह टिकैत कई बार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनके गांव के लोग बताते हैं कि वह कई महीने आगरा के पागलखाने में रहे हैं। जब भी टिकैत पर पागलपन का दौरा पड़ा, वह अपने को भगवान का अवतार बताते हुए देश में रामराज्य कायम करने का राग अलापते रहे।

लोग बताते हैं कि टिकैत का पागलपन सहज ही नहीं था। जब-जब उनकी सरपंची पर आंच आयी वह विक्षिप्त हो गये। उन पर पहला दौरा १९७२ में पड़ा था। उस समय वह पंचायत के सरपंच थे। झाड़खेड़ी गांव की एक लड़की, सिसौली के सतवीर सिंह को ब्याही थी। सतवीर सिंह ने पत्नी को घर से निकाल दिया। लड़कीवालों ने यह मामला पंचायत में रखा। टिकैत सरपंच थे। उन्होंने सतवीर सिंह का हुक्का-पानी बंद करने का निर्णय सुना दिया।

कुछ ही दिनों बाद सतवीर ने अन्य पंचों से बातकर दुबारा इस मामले पर पंचायत बुलाने का आग्रह किया। इस बार पंचायत ने बहुमत से टिकैत के फैसले को उलट दिया। पंचों का कहना था कि टिकैत ने अपना फैसला देने से पूर्व न तो सतवीर की बात सुनी थी और न ही दोनों पक्षों में सुलह कराने का ही कोई प्रयास किया था। पंचायत ने सतवीर का हुक्का-पानी खोल दिया। टिकैत ने इसे अपनी चौधराहट की गरिमा के प्रतिकूल समझा और इसी सोच में पागल हो गये।

उन्होंने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया, "मेरा नहीं भगवान का अपमान हुआ है। न्याय तो अब होगा। मैं युधिष्ठिर हूं। मां कुन्ती को वापस लाओ (सतवीर की पत्नी को वह महाभारत की कुन्ती कहने लगे थे)।"

इसी के साथ ही टिकैत ने पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दीं। घरवालों को लगा कि टिकैत पर कोई साया है। झाड़-फूंक के लिए ओझा बुलाये जाते। टिकैत उन पर बरस पड़ते, "अबे तू भगवान को परेशान करने आया है। मेरी बात मान। न्याय की बात कर, वरना भस्म कर दूंगा।"

उनकी दिन-प्रतिदिन बढ़ती हरकतों से परेशान होकर घरवालों ने उन्हें नीम के पेड़ से बांधकर रखना शुरू कर दिया। इसके बाद भी जब उनका चीखना-चिल्लाना बंद नहीं हुआ, तो उनके छोटे भाई भोपाल सिंह उन्हें आगरा ले गये। कई महीनों तक टिकैत पागलखाने में रहे। वहां से ठीक होकर आये, तो करीब एक साल तक ठीक-ठाक रहे, लेकिन फिर असामान्य हो गये।

दुबारा उनका इलाज गुड़गांव (हरियाणा) के जाड़सीकरी गांव में रहनेवाले एक ओझा के यहां हुआ। वहां से ठीक होकर जब गांव लौटे तो फिर दो वर्ष तक गायब रहे। घरवाले इस बारे में कहते हैं, "चौधरी अज्ञातवास पर चले गये थे।"

वर्ष १९८२ में उन पर फिर दौरा पड़ा। इस बार का दौरा भी उनकी चौधराहट को लेकर था। दरअसल, मानसिक रूप से ठीक न होने की वजह से पंचायत में उन्हें नहीं बुलाया जाता था। इस बात से वह काफी नाराज थे।

१२ फरवरी, १९८२ को सिसौली के जनता इंटर कालेज की प्रबंध समिति के विवाद को निपटाने के लिए पंचायत बुलायी गयी थी। टिकैत उसमें जाना चाहते थे, लेकिन घरवालों ने मना कर दिया। इस पर वह मारपीट पर उतारू हो गये। किसी प्रकार उन्हें काबू में कर नीम के पेड़ से बांध दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह रस्सी तुड़ाकर पंचायत में पहुंच गये। वहां उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, "इस पंचायत में फैसला मैं दूंगा। नहीं तो ११ कनस्तर मिट्टी का तेल और २१ मन लकड़ी होगी, उसी पर मेरी चिता बनेगी। यहां नहीं, तो 'ऊपर' जाकर फैसले करूंगा। मेरी चौधराहट मेरे बड़े लड़के नरेश के सिर बांध दी जाये।"

यह देख गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चौधरी बलजीत सिंह, उन्हें समझाने पहुंचे। टिकैत ने उन्हें उठाकर पटक दिया। इस पर झगड़ा बढ़ गया। पंचायत भंग हो गयी।

जब कभी भी टिकैत बंधन से छूट जाते थे, तो गांव में घूम-घूमकर चिल्लाते थे, "भगवान ले लो।" गांव के ६० वर्षीय हुक्मा ने जब एक बार टिकैत को डांट दिया, तो गुस्से में टिकैत ने उसकी पिटायी कर दी। बेचारी की हड्डी-पसली टूट गयी।

गांव में धारा नाम का एक आदमी रहता था। टिकैत एक दिन उसके पीछे पड़ गये। धारा ने पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन टिकैत भिड़ गये। वह उनसे इक्कीस था। उसने टिकैत की धुनायी कर दी। तब तो टिकैत ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया, "इसने भगवान को पीटा है, इसे गांव से बाहर निकालो।"

पिछले दो साल से टिकैत सामान्य हैं। लेकिन यह बात उनके स्वभाव से जुड़ गयी है कि जब भी उन्हें लगा कि उनका महत्व घट रहा है, वह विक्षिप्त होने लगते हैं। उनके कई विरोधी इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जैसे भी हो कोई ऐसी घटना घट जाये कि टिकैत का महत्व थोड़ा कम हो और उन्हें पेड़ से बांधने की नौबत फिर आ जाये।

—सुरेश त्रिवेदी

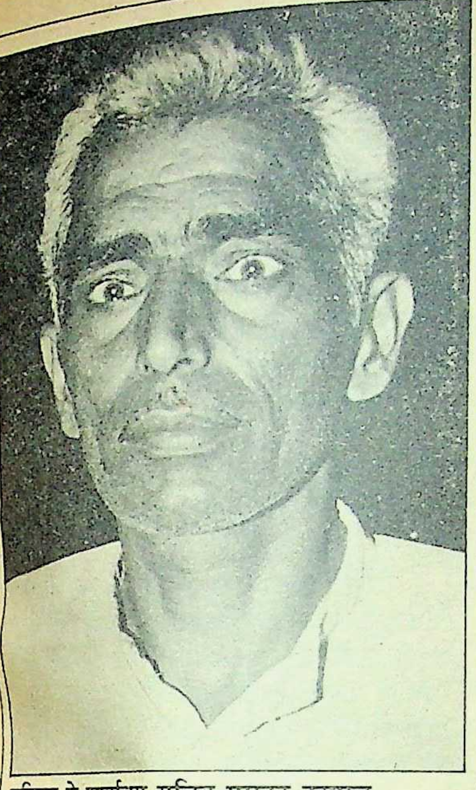
यूनियन के कार्यालय सचिव मास्टर हरपाल

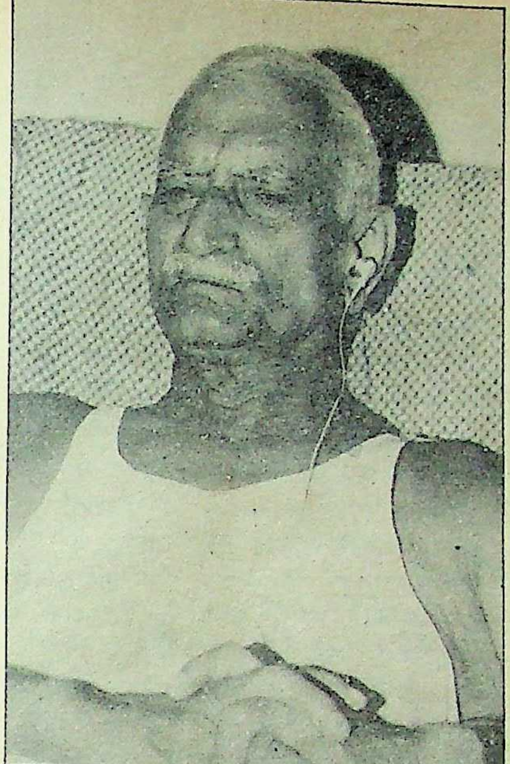
टिकैत के विरोधी: चौधरी बलवंत सिंह

घटनाओं के विरोध में आयोजित सभा में तो टिकैत गये, लेकिन मेरठ-मुजफ्फरनगर मार्ग पर बस से उतार कर जिन ११ अल्पसंख्यकों की हत्या की गयी, उस घटना पर टिकैत ने आज तक कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। ठीक इसी तरह उनका पंचायती निर्णय भी जाटवादी होता है। माण्डी गांव के राजेंद्र को बिना किसी सबूत के दण्ड दिया गया, लेकिन सिसौली में धीमर जाति की एक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले जाट युवक को टिकैत ने यह कहकर बरी कर दिया कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं है।

वैसे तो टिकैत, भारतीय किसान यूनियन का बैनर लेकर ही नेता बने हैं, लेकिन जिन लोगों ने टिकैत को यूनियन का छोटा सा पद सौंपा था, उन्हें टिकैत आज पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। यूनियन के जन्मदाता तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष राव हरलाल ने किसानों की समस्याओं को लेकर १३ अगस्त को दिल्ली में बोट क्लब पर धरना दिया था, लेकिन टिकैत की सभा जैसी भीड़ का नजारा वहां नहीं था। उसी दिन राव हरलाल ने सुखवीर सिंह को यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा धर्मपाल सिंह (निवासी सहदरा, मेरठ) को यूनियन की उत्तर प्रदेश शाखा का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। अब हालत यह हो गयी है, असली यूनियन भले हर हरपाल सिंह की है, लेकिन डंका तो टिकैत का ही बज रहा है।

टिकैत और राजनीति: टिकैत को राजनेताओं से सख्त परहेज है, एक ओर वह किसानों को लगान न देने और सरकार को अपना अनाज न बेचने का आदेश देकर सरकार के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं, तो दूसरी ओर वह राजीव गांधी व वीर बहादुर सिंह ही नहीं वी०पी० सिंह, देवीलाल जैसे नेताओं को भी एक सिरे से खरी-खरी सुना रहे हैं। वे जब भी टिकैत से मिलते हैं या अपने बीच उन्हें बुलाते हैं, तो हर बार अपमानित होते हैं, फिर भी चाहते हैं कि टिकैत की कृपा उन पर बनी रहे, जबकि उन्होंने राजनेताओं के प्रति अपनी घृणा को कभी छुपाया नहीं। उनका कहना है, "इन्हीं राजनीतिज्ञों ने सोने की चिड़िया कहलानेवाले इस देश को बरबाद किया है। हमने अब तक इन पर विश्वास किया, यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसका खमियाजा हम किसानों को दरिद्रता की स्थिति तक पहुंचकर भुगतना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।"

अब तक पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने टिकैत की किसान यूनियन को वोट बैंक मानकर काफी दांवपेंच खेले, लेकिन टिकैत ने उन्हें मुंह नहीं लगाया। यूनियन में घुसपैठ का पहला प्रयास लोकदल (अ) अध्यक्ष अजीत सिंह ने किया था। उन्हें भ्रम था कि यूनियन में जाटों का वर्चस्व है और उनके पिता ने इनकी रहनुमाई की थी, इसलिए यूनियन उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेगी। यही सोचकर वह ६ मार्च की शोकसभा में पहुंच गये जो पहली मार्च को किसान-पुलिस संघर्ष में शहीद हुए जयपाल और अकबर नामक किसानों के शोक में आयोजित हुई थी। मृतकों के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए अजीत सिंह ने किसान यूनियन को अपनी पार्टी का समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। इस पर टिकैत ने कहा, "तब कहां थे, जब हम पर गोली चली थी। जाट हो, तो क्या हुआ। हमें राजनीतिज्ञों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। अगर साथ काम करना चाहते हो, तो पहले पार्टी छोड़ो।"

टिकैत, राजा विश्वनाथ प्रताप को ईमानदार मानते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वह किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने राजा को न्योता भेजा था कि वह १ अप्रैल को शामली में होनेवाली किसान रैली में शामिल हों। उस समय राजा कांग्रेस-इ पार्टी में ही थे, इसीलिए शायद उन्होंने किसान रैली में जाना उचित नहीं समझा। अब टिकैत कहते हैं, "राजा ईमानदार भले ही हों, लेकिन दब्बू हैं। हमें दब्बू आदमी कतई पसंद नहीं हैं।"

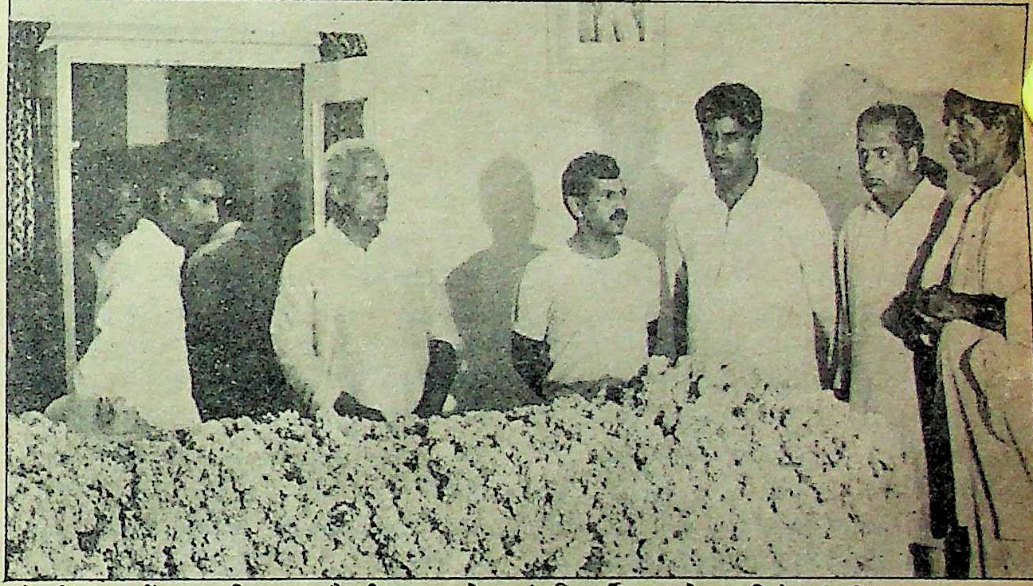
चौधरी चरण सिंह का विकल्प: चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए टिकैत (दायें)

जब टिकैत किसानों की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आ गये, तो वीर बहादुर सिंह को भी लगा कि उन्हें पटाये बिना काम नहीं चलेगा। टिकैत प्रभावित ज्यादातर इलाके हरियाणा की सीमा से लगे हुए हैं। हरियाणा में अपनी पार्टी की पराजय वीर बहादुर सिंह हाल ही में देख चुके थे। इसीलिए वह टिकैत से बातचीत का मौका ढूंढने लगे।

उमाशंकर दीक्षित के संबंधी कमलेश पाण्डेय और सिसौली के ही पूरण सिंह के सहयोग से यह तय हुआ कि सिसौली गांव में ११ अगस्त को आयोजित

टिकैत और उनकी सल्तनत

सिर पर मटमैली-सी टोपी, शरीर पर बिना प्रेस किया हुआ साधारण सा धोती-कुर्ता, नंगे पैर, साढ़े छह फुट का गठीला शरीर, ढलती उम्र (५२ वर्ष). देखने में निपट गंवार— यही हुलिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेताज बादशाह महेंद्र सिंह टिकैत का। उनका गांव सिसौली उनकी सल्तनत की राजधानी है। इस बेताज बादशाह के बैठने के लिए वहां न तो कोई सिंहासन है और न कुरसी-मेज। जमीन पर अपनों के बीच बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते या बीड़ी का कश खींचते टिकैत को उस भीड़ के बीच पहचानना सरल नहीं है। दिल्ली दरबार से कहीं ज्यादा भीड़ टिकैत के दरबार में रहती है।

महेंद्र सिह दो भाई और एक बहन हैं। छोटे भाई भोपाल सिंह ने गाजियाबाद में एक छोटी-सी फैक्ट्री लगा रखी है। एकमात्र बहन महेंद्री की शादी हो चुकी है।.वह अपने पति सरदार सिंह वर्मा के साथ बड़ौत (मेरठ) के गुराना गांव में रहती है। टिकैत के चार पुत्र नरेश, राकेश, नरेंद्र और सुरेंद्र तथा तीन पुत्रियां, बाला, ओमवीरो और विमला हैं। दो बड़े पुत्रों और तीनों पुत्रियों की शादी हो चुकी है। टिकैत ने अपनी छोटी बेटी विमला का विवाह ८४ गांव की सबसे बड़ी 'देशखाप' के चौधरी बड़ौत निवासी सुखवीर सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह से किया है। इन दिनों किसान पंचायत यूनियन को लेकर टिकैत की अपने समधी सुखवीर सिंह से ठनी हुई है। टिकैत की अनपढ़ पत्नी बलजोरी अपने पति के बढ़ते प्रभाव से रोमांचित हैं। वह कहती हैं, "वो तो एक दिन पूरे देश को बादशो (बादशाह) बनेगो।" टिकैत भी स्वयं को राजबंशी साबित करते हैं। वह कहते हैं, "आज से १३५० वर्ष पूर्व राजा हर्षवर्द्धन ने हमारे पूर्वज राजा रघु के यहां अपनी पुत्री का टीका (विवाह) किया था। उस समय राजा हर्षवर्द्धन ने घोषणा की थी कि मेरी पुत्री से होनेवाला वंश 'टिकैत' की.पदवी से विभूषित होगा। चूंकि हम उसी वंश की संतान हैं, इसलिए हम नाम के आगे टिकैत लगाते हैं।"

दिनचर्या : टिकैत बड़े सवेरे चार बजे उठ जाते हैं। सामान्य दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद वह यूनियन कार्यालय में पड़ जाते हैं, कुछ घंटे सोने के बाद फिर थोड़ी देर तक पूजा-पाठ करते हैं। तब तक किसानों की भीड़ टिकैत के घर के सामने जुटने लगती है। 'किसान यूनियन जिंदाबाद' के उद्घोष के साथ यूनियन की प्रातःकालीन सभा 'जनता दर्शन' से शुरू होती है। भीड़ में कहीं भी बैठकर टिकैत हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। तब कार्यालय सचिव मास्टर हरपाल खड़े होकर सूचना पढ़ते हैं कि किस-किस गांव में यूनियन की सभा के लिए टिकैत को आमंत्रित किया गया है, किस गांव में क्या समस्या है और किन-किन मामलों पर आज मंत्रिमंड़ल (पंचायत) में विचार होना है। इसके बाद शुरू होता है, प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण। दरबार में हाजिरी देने आये सूबेदारों (यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्षों) से संक्षिप्त सलाह-मशविरे के बाद टिकैत 'जनता' के प्रार्थना-पत्रों पर सचिव द्वारा लिखे गये आदेश के नीचे अपने दस्तखत बनाते हैं। टिकैत के दस्तखत हुए नहीं कि मानो संबंधित व्यक्ति का काम हो गया। थानेदार से लेकर कमिश्नर तक किसी सरकारी अधिकारी में यह हिम्मत नहीं होती जो टिकैत के दस्तखतवाले प्रार्थना-पत्रों को नजरअंदाज कर दे।

सुबह साढ़े दस बजे तक जनता का जमावड़ा टिकैत के आवास से उठकर मंदिर प्रांगण में आ जाता है, जहां टिकैत का खास दरबार लगता है, अर्थात पंचायत की कार्यवाही शुरू होती है। हर एक को उसमें भाग लेने का अधिकार है। बीच-बीच में टिकैत की टोका-टोकी भी चलती रहती है। दोपहर में किसान यूनियन की ओर से सामूहिक भोजन की व्यवस्था रहती है। दिन ढलते ही पंचायत उठकर फिर टिकैत के आवास पर आ जाती है। देर रात तक फैसले होते रहते हैं। फिर साथियों के साथ भोजन के बाद टिकैत बिना बिस्तरवाली किसी खाट पर पड़ जाते हैं, कुछ घण्टे सोने के बाद फिर अगले दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है।

कानून-व्यवस्था : टिकैत प्रभावित क्षेत्र के लोग बताते हैं कि टिकैत ने अपनी प्रजा के लिए कई कड़े कानून बना रखे हैं। यद्यपि टिकैत और उनके साथी ऐसे किसी कानून के अस्तित्व से इनकार करते हैं, लेकिन इस अघोषित कानून व्यवस्था के भुक्तभोगियों ने 'माया' को बताया कि तितावी थाना क्षेत्र में पड़नेवाले नगलागांव में टिकैत ने अपना एक अलग थाना स्थापित कर रखा है। किसान सेना के लोग ही यहां थानेदार और सिपाही के पद पर तैनात हैं। किसी भी आपराधिक मामले की रिपोर्ट पहले यहीं दर्ज करायी जाती है। यहीं एक छोटी जेल (हवालात) भी है। इसी जेल में पकड़े गये अपराधी को बंद किया जाता है, फिर उसे पंचायत के सामने पेश किया जाता है। पंचायत किसी कथित अपराधी को आर्थिक दण्ड की सजा सुनाती है और वह अपराधी यदि जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे शाहपुर इलाके के रसूलपुर जाटान गांव में स्थित जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया जाता है।

पंचायत दो प्रकार के दण्ड देती है, आर्थिक और शारीरिक। शारीरिक दण्ड नूनी खेड़ा और मुंडभर गांव में दिया जाता है। वहां कथित अपराधी को पेड़ से उलटा लटकाकर अपराध कबूल करवाया जाता है। माण्डी गांव के पल्टू ने यह सजा भोगी है। पंचायत ने अपनी तहसीलें बना रखी हैं। इन्हें 'थांबा' कहा जाता है। एक थांबे में ५ से १२ गांव रखे जाते हैं। सोरम (सौरों) कस्बा पंचायत यानी यूनियन की कमिश्नरी है और सिसौली राजधानी।

जिन-जिन गांवों में यूनियन की इकाई गठित है, वहां ग्राम प्रधान के पद का कोई महत्व नहीं रह गया है। यूनियन की इकाई ही गांव में अपनी पंचायत करती है। इन पंचायतों में हुए निर्णय की अपील उस 'थांबे' की पंचायत में की जाती है, जिस थांबे में वह गांव आता है। थांबे की पंचायत के ऊपर सर्वोच्च पंचायत सिसौली में है, जहां विवादों और अपराधों का अंतिम निर्णय महेंद्र सिंह टिकैत करते हैं। यह पंचायत माह की ३ और १७ तारीख को बैठती है। वैसे, विशेष प्रयोजन पर पंचायत कभी भी बुलायी जा सकती है। सुनवाई के लिए यूनियन के पैड पर संबंधित व्यक्ति को बाकायदा नोटिस जाती है। इसकी दो बार अवहेलना करने पर 'गैर जमानती' वारंट की तरह 'किसान सेना' के सिपाही उसे जबरन पकड़कर पंचायत में उपस्थित करते हैं। बिना पूर्व अनुमति पुलिस के पास जाना यूनियन के नियमों के विरुद्ध है। यदि कोई ऐसा करता है, तो उस पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। बरवाला गांव का चौकीदार एक घटना की रिपोर्ट करने थाने चला गया, पुलिस तो नहीं आयी। लेकिन पंचायत ने उस पर पांच सौ रुपए का आर्थिक दण्ड घोषित कर दिया। कहते हैं, बाद में टिकैत से माफी मांगने पर उसे इस सजा से मुक्त किया गया।

किसान सेना : कुर्ता-पायजामा, सिर पर हरे बार्डर की सफेद टोपी, सीने पर किसान सेना का हरा-सफेद बिल्ला— यही पोशाक है, टिकैत की किसान सेना के जवानों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव है, वहां शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना, रात्रि गश्त, सभाओं की व्यवस्था करना तथा 'रणसिंघा' बजाकर किसानों को एकत्र करना किसान सेना का काम है। पहली मार्च, १९८७ को हुई पुलिस-किसान-मुठभेड़ के मामले में २५० किसानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दायर किये थे। किसानों को

गिरफ्तारी से बचाने के लिए यूनियन के नेताओं ने जिस 'सुरक्षा सेना' का गठन किया था, आज उसे ही 'किसान सेना' का नाम दे दिया गया।

किसान सेना में ही कई विशेष सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया है। इन सुरक्षा दस्तों का कार्य केवल टिकैत की सुरक्षा करना है। इसमें २५ हथियारबंद लोग 'कमाण्डो' की तरह टिकैत की सुरक्षा के लिए उन्हें घेरकर चलते हैं। इस सुरक्षा दस्ते की मरजी के बगैर कोई भी व्यक्ति घेरा तोड़कर टिकैत से मिल नहीं सकता। टिकैत से मिलने के लिए पहले इनसे अनुमति लेनी पड़ती है। सुरक्षा दस्ते में २० से ३५ वर्ष के वे लोग होते हैं जो अच्छी तरह से हथियार चलाना जानते हैं।

मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक एस०एन० सिंह ने बताया, "अभी तक किसान सेना और उसकी इकाई सुरक्षा सेना ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसके लिए पुलिस को कार्यवाही करनी पड़े।"

टिकैत की बादशाहत में अनेक लोग तकलीफ में हैं, लेकिन उन्होंने जिस पंचायती व्यवस्था को मजबूत बनाया है, उससे अमन-चैन भी कायम हो रहा है। गांवों में दुराचरण और गुंडागर्दी आदि की घटनाओं में भारी कमी आयी है। शादी-ब्याह में दहेज के लेन-देन और दिखावे पर भी टिकैत ने रोक लगा दी है। बारातों में अब पांच से ग्यारह तक ही बाराती जाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जब गांववालों ने ग्यारह से अधिक बाराती आने पर बारात को गांव के बाहर रोक लिया और दूल्हे एवं दस अन्य लोगों के अलावा अन्य बारातियों को वापस लौटना पड़ा।

गैरजाट क्षेत्रों में प्रभाव : इन सब बातों से टिकैत का प्रभाव गैरजाट क्षेत्रों में भी बढ़ना शुरू हो गया है। ६ सितंबर, १९८७ को मुजफ्फरनगर के ग्राम कुतुबपुर में टिकैत का जो भव्य स्वागत हुआ वह अभूतपूर्व था। लगभग ४ किलोमीटर लंबे जुलूस में सबसे आगे ५० घुड़सवार थे। उसके पीछे बैलगाड़ियों की लंबी कतार और दो किलोमीटर तक पैदल चलते किसानों का समूह था। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बेताज बादशाह टिकैत एक खुली जीप पर खड़े किसानों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उनके १५ सशस्त्र अंगरक्षक जीप में उनके साथ थे; जीप के दोनों ओर खुली रिवाल्वर लिए कुछ लोग चल रहे थे

चौधरी चरण सिंह के बाद टिकैत ही जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। किसानों में बढ़ते उनके प्रभाव ने उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह की सरकार की नींद हराम कर दी है।

—अजय कुमार

श्याम वीर राठी

आतंकित : पंडित जगन्नाथ

जिलाधिकारी : राजेन्द्र सिंह यादव

किसान यूनियन की सभा में वीर बहादुर सिंह किसान यूनियन की मांगों को स्वीकार करने की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री को उम्मीद थी कि इससे वह किसानों का दिल जीत लेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। ११ अगस्त को सिसौली में सभा तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन टिकैत ने 'कर्जे माफी' की नयी मांग रखकर वीर बहादुर सिंह की वहां ऐसी बेइज्जती की, जिसकी वह कल्पना तक नहीं कर सकते थे। (देखिए 'माया', १५ अगस्त, १९८७)।

राजनीति से जुड़े लोगों को अपमानित करने का कोई मौका टिकैत नहीं चूकते। मेरठ के सुरूरपुर कस्बे में पुलिस की गोली से दो छात्रों की मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के विरोध में ३१ जुलाई को सुरूरपुर में एक विरोध सभा आयोजित की गयी थी, जिसमें अजीत सिंह के अलावा मेरठ के लोकदल विधायक भोपाल सिंह तथा देश खाप के मुखिया सुखवीर सिंह मंच पर मौजूद थे। टिकैत उस सभा में जा पहुंचे तथा यह कहते हुए मंच पर नहीं गये; "जहां राजनीतिक कपटी बैठे हों, उस मंच पर मैं नहीं जाऊंगा।" इसके बाद वह एक टैक्टर पर खड़े होकर भाषण करने लगे। सारी भीड़ टिकैत के सामने आ गयी। ठीक इसी तरह मुजफ्फरनगर के वकील राजकुमार बालियान की पुलिस द्वारा हत्या के विरोध में आयोजित सभा से टिकैत यह कहते हुए उठकर चले गये थे, "मैं चोरों (राजनेताओं) के साथ नहीं बैठ सकता।" वहां भी मंच पर कई राजनेता बैठे थे।

यह टिकैत का ही रुतबा है कि विश्व बैंक की नौकरी छोड़कर आये महाराष्ट्र संगठन नामक किसान संगठन के नेता शरद जोशी, बंधुआ मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश सहित पंजाब और गुजरात के अनेक नेता टिकैत के पास पहुंचने लगे। शरद जोशी ने टिकैत को यह भरोसा दिलाकर किसानों की अंतरराज्यीय समन्वय समिति का अध्यक्ष बनवा दिया कि इस संगठन का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। इस बीच टिकैत ने घोषणा कर दी कि किसान यूनियन के जन्मदिन अर्थात १७ अक्तूबर को दिल्ली में लाखों किसानों का प्रदर्शन करेंगे।

उधर किसानों की अंतरराज्यीय समन्वय समिति ने भी १७ अक्तूबर को 'दिल्ली चलो' का आह्वान कर दिया। इस समिति से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के किसान संगठन सम्बद्ध हैं। संयोजन समिति ने १७ अक्तूबर को दिल्ली चलो का नारा इसीलिए दिया, ताकि टिकैत द्वारा एकत्र भीड़ का फायदा दूसरे राज्यों के किसान संगठन भी उठा सकें।

१७ अक्तूबर की रैली और 'दिल्ली चलो मार्च' की रूपरेखा पर विचार करने के लिए सितंबर को संयोजन समिति की विशेष बैठक दिल्ली में बुलायी गयी। इसी बैठक में पंजाब किसान यूनियन के विजय जवाधिया, भूपेंद्र सिंह मान, बलवीर सिंह राजेवाल, आंध्र किसान संगठन के शंकरा रेड्डी, गुजरात के किसान नेता गुनवंत भाई और चुन्नी भाई वैद, कर्नाटक किसान यूनियन के नंजुद स्वामी तथा शेतकारी संगठन के शरद जोशी के अलावा विभिन्न प्रांतों से आये लगभग ५० किसान नेता मौजूद थे। महेंद्र सिंह टिकैत भी बैठक में भाग लेने पहुंचे। बैठक में जैसे ही शरद जोशी ने यह मुद्दा उठाया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया जाये या नहीं ? टिकैत बमक उठे। वह बोले, "कोई भी साझा कार्यक्रम तय करने से पहले राजनीति से रिश्ते का मसला तय हो जाना चाहिए।"

शरद जोशी सहित तमाम किसान नेता इस पक्ष में थे कि जहां भी किसानों का हित हो, वहां राजनीतिक दलों का समर्थन लिया जाना चाहिए। जहां तक विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रश्न है, वे किसानों के हितैषी हैं। इसीलिए उनका समर्थन किया जाना चाहिए।

टिकैत ने इसका जबरदस्त विरोध किया और बैठक से उठकर चले गये। इसी के बाद संयोजन समिति मे १७ अक्तूबर को 'दिल्ली चलो' मार्च का निर्णय बदलकर इसके लिए अगले वर्ष १२ मार्च की तारीख तय कर दी। दूसरी ओर टिकैत ने भी अपनी १७ अक्तूबर को होनेवाली रैली को स्थगित करते हुए घोषणा की कि वह अगले वर्ष दिल्ली में ४० लाख किसानों का प्रदर्शन अपने बलबूते पर करेंगे।

राजनीति और राजनेताओं से टिकैत की नफरत को जो राजनेता अभी तक टिकैत की चाल

टिकैत का आधार क्या है?

अगर इस समय मध्यावधि चुनाव हों और राजीव गांधी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह 'टिकैत' के प्रभाववाले इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो वह भारी बहुमत से जीतेंगे और यदि अपने को गैरराजनीतिक कहनेवाले महेंद्र सिंह 'टिकैत', स्वयं राजीव गांधी के विरुद्ध मैदान में उतर आयें, तो उन्हें (टिकैत को) ३४ प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिलेंगे।

टिकैत प्रभावित इलाके के करीब पांच हजार से अधिक मतदाताओं से बात करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है। 'माया' की टीम ने सात दिनों (२५ से ३१ अगस्त) तक मुजफ्फरनगर और मेरठ के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं से इस बारे में स्पष्ट सवाल पूछे। इन दोनों जिलों के तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों—बागपत, कैराना और मुजफ्फरनगर के मतदाताओं के सामने 'माया' ने अपने सर्वेक्षण में मुख्य रूप से पांच सवाल रखे थे। पहला—अगर राजीव गांधी यहां से चुनाव लड़ें और महेंद्र सिंह टिकैत उनके विरुद्ध उम्मीदवार हों तो कौन जीतेगा? दूसरा—राजा और टिकैत के आमने-सामने चुनाव लड़ने पर कौन जीत सकता है? तीसरा—अजीत सिंह और टिकैत के बीच चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। चौथा और पांचवां सवाल यह था कि राजा और अजीत तथा राजा और राजीव के बीच सीधे मुकाबले में जीत किसकी हो सकती है?

सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों से ये प्रश्न पूछे गये। इनमें ६१ प्रतिशत मतदाताओं का कहना था कि टिकैत के विरुद्ध राजीव गांधी की जीत निश्चित है। केवल ३२ प्रतिशत मतदाता ही टिकैत के पक्ष में थे। जबकि ७ प्रतिशत मतदाताओं का कहना था, "कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा?"

हरिजनों में ज्यादातर मतदाताओं का कहना था, "अगर जाटों की लाठी पर मतदान के समय रोक लग गयी, तो राजीव गांधी को कोई ताकत हरा नहीं सकती है।" इस बारे में टिकैत के ही गांव सिसौली की हरिजन बस्ती में रहनेवाली श्रीमती चंद्रा (५० वर्ष) का कहना था, "हम आज तक कभी वोट नहीं डाल पाये। जाटों की लुगाई (स्त्रियां) हमारे नाम पर वोट डालती हैं।"

राजीव गांधी और महेंद्र सिंह टिकैत

मतदाता	राजीव जीतेंगे	टिकैत जीतेंगे	पता नहीं
जाट	२	२३	—
हरिजन	८	१	१
सवर्ण	२१	२	२
मुस्लिम	८	१	१
पिछड़ा वर्ग	७	२	१
अन्य	१५	३	२
योग	६१	३२	७

(प्रतिशत)

राजा और टिकैत

मतदाता	राजा जीतेंगे	टिकैत जीतेंगे	पता नहीं
जाट	४	२१	—
हरिजन	७	२	१
सवर्ण	२३	२	—
मुस्लिम	६	१	३
पिछड़ा वर्ग	८	१	१
अन्य	१६	२	२
योग	६४	२९	७

(प्रतिशत)

अजीत सिंह और टिकैत

मतदाता	अजीत जीतेंगे	टिकैत जीतेंगे	पता नहीं
जाट	६	१८	१
हरिजन	६	१२	२
सवर्ण	९	११	५
मुस्लिम	२	६	२
पिछड़ा वर्ग	७	१०	३
योग	३०	५७	१३

(प्रतिशत)

सिसौली के ही एक टैक्सी ड्राइवर महेंद्र (हरिजन) का कहना था, "चुनाव में कोई बड़ा हो जाये, जीतेगी जाटों की लाठी।"

लेकिन मुजफ्फरनगर के मालगोदाम रोड पर पान की दुकान करनेवाले हरपाल सिंह बताते हैं, "इस देश में राजीव गांधी का आधार है, जबकि टिकैत, धोखा है। वह थोड़े दिन में अपने आप ठण्डे हो जायेंगे। राजीव की बात तो दूर, टिकैत के खिलाफ राजा और अजीत सिंह भी आसानी से जीत जायेंगे।"

बागपत चौराहे पर स्कूटर की रिपेयरिंग करनेवाले सलीम का कहना था, "राजीव को छोड़कर बाकी और कोई टिकैत को नहीं हरा सकता।"

टिकैत को कुछ महीने पूर्व किसान यूनियन में एक छोटा-सा पद देनेवाले, यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सुखवीर सिंह (टिकैत के समधी) और कोषाध्यक्ष नाहर सिंह आज कल टिकैत से बुरी तरह नाराज हैं। वे कहते हैं, "राजीव के मुकाबले टिकैत की जमानत तक नहीं बचेगी, क्योंकि जो लोग उनकी सभा में आते हैं वह तो बस उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनने या फिर समय काटने आते हैं। टिकैत के मुकाबले राजा और अजीत भी आसानी से जीत जायेंगे।"

महेंद्र सिंह टिकैत के दामाद सुरेंद्र सिंह यह बात दावे के साथ कहते हैं, "टिकैत चुनाव कतई नहीं लड़ेंगे। उनके समर्थन पर ही राजा या अजीत चुनाव जीत सकते हैं।"

बड़ौत स्थित जे०पी० कालेज के अध्यापक रवीश चंद्र का विचार है, "टिकैत का प्रभाव अब कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका हर काम मूर्खतापूर्ण होता है। टिकैत, राजीव, राजा और अजीत तीनों से बुरी तरह हार जायेगा।"

राजा और टिकैत के बीच चुनाव में कौन जीतेगा? इस बारे में ६४ प्रतिशत मतदाताओं की राय, राजा के पक्ष में थी, जबकि ७ प्रतिशत मतदाता यह कहकर टाल गये, 'पता नहीं'। केवल २९ प्रतिशत मतदाताओं का कहना था, "टिकैत जीतेंगे।" ऐसा कहनेवालों में सर्वाधिक जाट मतदाता थे, लेकिन टिकैत और अजीत सिंह में से वे किसे चुनेंगे, इस सवाल पर ५७ प्रतिशत मतदाता टिकैत के पक्ष में थे। अजीत सिंह के समर्थक केवल ३० प्रतिशत ही मतदाता मिले। दो जाटों की सीधी लड़ाई में पता नहीं कौन जीतेगा, कौन नहीं, यह कहनेवाले मतदाताओं की संख्या (१३ प्रतिशत) भी कम नहीं थी।

राजा और अजीत में ६६ प्रतिशत मतदाता राजा के पक्ष में और २३ प्रतिशत अजीत के पक्ष में थे। जाटों का वह वर्ग जो स्थानीय नेता सत्यपाल मलिक के प्रभाव में है, वह राजा के पक्ष में है।

मतदाताओं से पूछे गये सबसे अहम सवाल कि राजीव और राजा में कौन जीत सकता है, के जवाब में ४९ प्रतिशत मतदाताओं ने राजीव का समर्थन किया, जबकि राजा के पक्ष में ४१ प्रतिशत मतदाता थे। इसके अतिरिक्त १० प्रतिशत मतदाता, समय की नाजुकता को देखते हुए यह कहकर चुप हो गये, "टक्कर कांटे की होगी, हार-जीत भी थोड़े वोटों से होगी। लेकिन कौन जीतेगा, कह नहीं सकते।"

सर्वेक्षक: अजय कुमार, सुरेश द्विवेदी, राजेंद्र कुमार और मुजम्मिल हुसैन

राजा और अजीत

मतदाता	राजा जीतेंगे	अजीत जीतेंगे	पता नहीं
जाट	८	१६	१
हरिजन	७	७	२
सवर्ण	२२	१	२
मुस्लिम	७	१	२
पिछड़ा वर्ग	६	३	१
अन्य	१६	१	३
योग	६६	२३	११

(प्रतिशत में)

राजीव और राजा

मतदाता	राजीव जीतेंगे	राजा जीतेंगे	पता नहीं
जाट	६	१७	२
हरिजन	६	३	१
सवर्ण	१२	११	२
मुस्लिम	८	१	१
पिछड़ा वर्ग	७	१	२
अन्य	१०	८	२
योग	४९	४१	१०

(प्रतिशत में)

चंद्रवल्ली सिह

समझते थे, उनके मुगालते शरद जोशी प्रसंग से दूर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्षी एकता के लिए गैरवामपंथी कांग्रेस-इ विरोधी पार्टियों के सूरजकुण्ड में हुए सम्मेलन में टिकैत को बुलाने की गलती देवीलाल ने कर दी। टिकैत अपने सशस्त्र साथियों के साथ पहुंचे और उन सभी पर बरस पड़े, "तुम सब आज राजीव को कोस रहे हो, जैसे यहां बैठे सब दूध के धुले हो। तुम्हारे १९७७ के राज में जितना किसान दुःखी हुआ, उतना कभी नहीं हुआ, किसानों का गन्ना खेत पर जला। उस तबाही ने किसान भाइयों की खूब कमर तोड़ी। तुम भाइयों ने भी कांग्रेसियों से कम उपद्रव नहीं किये, अब फिर कुरसी पाने के लिए दौड़ रहे हो।"

उस सभा में देवीलाल, वी०पी० सिंह, लालकृष्ण आडवाणी सहित ११ विपक्षी पार्टियों के नेता भौचक होकर टिकैत की बातें सुनते रहे। टिकैत वहां यह घोषणा करके चले आये, "वह भले ही किसी मंच पर कुछ कहने-सुनने चले जायें, पर किसी राजनीतिबाज को अपने मंच पर नहीं आने देंगे।"

अब हालात यह हैं कि टिकैत राजीव सरकार और वीर बहादुर सिंह की सरकार को भ्रष्ट व किसान विरोधी बताकर उनके खिलाफ इस कदर जेहाद छेड़े हुए हैं कि आज अपने इलाके से उन्होंने इनकी सरकारों को व्यावहारिक रूप से उखाड़ फेंका है, लेकिन वह वी०पी० सिंह आदि उन नेताओं के साथ भी नहीं है, जिन्होंने राजीव गांधी का तख्ता पलटने के लिए पूरे देश में जनजागरण अभियान छेड़ रखा है। कांग्रेस-इ और विपक्षी पार्टियां टिकैत का इस्तेमाल करना या उन पर अंकुश लगाना चाहती हैं। २३ अक्तूबर को शामली में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित किसान-मजदूर सम्मेलन का भी यही उद्देश्य था, लेकिन टिकैत किसी के भी काबू में नहीं आ रहे। वह समूची राजनीतिक व्यवस्था पर चोट करते हुए अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, देखना है कि देश की राजनीति में यह गैरराजनीतिक शख्सियत क्या-क्या गुल खिलाती है।

छाया: मनमोहन शर्मा, राजेंद्र कुमार

साक्षात्कार/ महेन्द्र सिंह टिकैत,

'हम किसी भी पार्टी को अपना मंच नहीं देंगे'

जब हम सिसौली पहुंचे, सूरज ठीक सिर पर था। गर्मी इतनी अधिक थी कि सारा शरीर पसीने से तर-बतर हो चुका था। गांव के बीचो-बीच एक टीले पर बने मंदिर के बाहर करीब तीन-चार सौ किसान इकट्ठे थे। अधिकतर के सिरों पर टोपियां थीं। उस दिन (३० अगस्त) टिकैत ने सिसौली में पंचायत बुला रखी थी। ये किसान आसपास के गांव के ही थे। मंदिर के ठीक बगल में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। गांववालों से पता चला कि मंदिर की इस जमीन पर टिकैत के निर्देश पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यालय का निर्माण हो रहा है।

पंचायत दो मामलों पर फैसले के लिए बुलायी गयी थी। पहला मुद्दा था—मंदिर के पीछे जमीन पर जिन गांववालों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें बेदखल किया जाये। दूसरा मामला, पड़ोस के गांव की एक शादीशुदा लड़की का था, जो ससुराल नहीं जाना चाहती थी। लड़कीवाले ने वर पक्ष से दहेज की वापसी की मांग की थी। जब लड़केवालों ने इन्कार कर दिया, तो कन्या-पक्ष ने टिकैत को दरखास्त देकर पंचायत में इसका फैसला करने का आग्रह किया था। टिकैत के सचिव मास्टर हरपाल ने एक दिन पूर्व ही नोटिस भेजकर वर पक्ष को पंचायत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। दोनों ही पक्ष उस समय पंचायत में मौजूद थे।

करीब तीन घंटे तक पंचायत चली। दोनों मामलों को लेकर काफी गर्मागर्मी हुई। आम लोगों की तरह महेन्द्र सिंह टिकैत भी ज़मीन पर बैठे, सबकी बात सुनते रहे। सारा मामला समझने के बाद टिकैत खड़े हुए, "सुणों... सुणों, बहुत हो लिया। सब सुण लिया मैणे। जमीन तो मंदिर की है। कब्जा नाजायज है, सो तो हटाणा ही पड़ेगा। मैं कहता हूं; दो तारीख तक कब्जा हटा लो। रही नुकसान की बात, अगर किसी भाई का कुछ नुकसान होवैगा, तो उसे यूनियन दे देवेगी पर कब्जा जरूर हटणा है।

"अब रही लड़कीवाली बात। सो भाई अगर लड़कावाला लड़की को न रखै, या निकाल देवे, तो लड़कीवाले को सामान वापस मांगने का हक है, लेकिन अगर लड़की न जावै, तो सामान मांगने का हक नहीं बनता। मैं तो कहूं दोनों आपस में बैठ लो, दो तारीख तक तय कर लो। आपस में मामला सुलझ जाये, तो अच्छा है। पंचायत में आकर क्यों बदनामी करो हो। दो तारीख तक तुम दोणों अगर न तय कर पावो, तो मेरे पे आ जाणा। मैं तय कर दूंगा।" इतना कहकर टिकैत बैठ गये और सब यह कहते हुए उठ गये, "ये रह्यों सही फैसला, टिकैत ने सही फैसलो कियो है।"

पंचायत की भीड़ धीरे-धीरे छट गयी थी। टिकैत अब केवल अपने चार-पांच खास लोगों से घिरे हुए थे। मैंने उनसे 'इन्टरव्यू' के लिए कहा, तो वह बोले, "मकान पर चलो, इत्मीनान से बात करूंगा।" पांच महीने पहले और अबके टिकैत में मुझे जमीन-आसमान का अन्तर लगा। अप्रैल, १९८७ में जब मेरी टिकैत से भेंट हुई थी, उस समय उनकी भाषा लट्ठमार और व्यवहार रूखा था। आज वह निहायत शरीफ और एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह लग रहे थे। अपने सचिव हरपाल को उन्होंने आदेश दिया, "इन्हें मकान पर ले चलो। कुछ खिलाओ-पिलाओ, अभी आकर बात करता हूं।"

पांच महीने में टिकैत के अपने मकान का रंग-रूप भी बदल गया था। मकान का जो हिस्सा कच्चा था, वह पक्का हो गया था। दुमंजिले मकान की छत पर किसान यूनियन का झंडा लहरा रहा था। मकान के ठीक सामने लगी नीम के नीचे ४०-५० लोग बैठे गपशप के साथ हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे।

बांयी ओर दूसरी नीम के नीचे एक दर्जन जानवर (६ भैंस, दो गाय और चार बैल) बंधे हुए थे। यह सब टिकैत की ही चल सम्पत्ति थी। मकान के निचले हिस्सेवाले एक कमरे में किसान यूनियन का दफ्तर था। इसी में वह 'अमर ज्योति' जल रही थी, जो पहली मार्च को शामली में किसान-पुलिस संघर्ष के बाद प्रज्वलित की गयी थी। ज्योति के ठीक पीछे दीवार पर कपड़े का एक बैनर लगा हुआ था। जिस पर लिखा था, 'भारतीय किसान यूनियन, अराजनैतिक, सिसौली (मुजफ्फर नगर) किसान एकता जिन्दाबाद, शहीद किसान जिन्दाबाद।' कोने में किसान यूनियन का एक बोर्ड भी रखा था, जिस पर 'भूखे किसान की मांग के ऊपर; सरकार का अत्याचार' लिखा हुआ था।' इसी कमरे में पहली मार्च को किसान-पुलिस संघर्ष में शहीद हुए दो लोगों के मालायुक्त चित्र लगे हुए थे। इन्हीं चित्रों के ठीक बगल में चौधरी चरण सिंह का भी एक चित्र लगा हुआ था, जिस पर बड़े करीने से माला टंगी हुई थी। कमरे में मौजूद लोहे की एक अलमारी में यूनियन के कागजात, चंदे की रसीदें, आय-व्यय का विवरण तथा 'संबंधित लोगों' की गोपनीय फाइलें रखी थीं।

अलमारी की चाबी हर समय मास्टर हरपाल के पास ही रहती है। यूनियन क़ार्यालय से सटा हुआ एक दूसरा बड़ा कमरा था, जिसमें अनाज से भरे बोरे रखे थे। उसमें करीब ६०-७० क्विन्टल अनाज होगा। यह सब किसानों से चन्दे के रूप में जमा किया गया था।

नीम के नीचे पड़े मोढ़े पर आकर टिकैत बैठ गये थे। लोगों ने उन्हें घेर लिया था। मुझे देखते ही बगलवाला मोढ़ा उन्होंने खाली कराया और बोले, "तुम सब थोड़ी देर थमों। मैं इनसे बात कर लूं, तब तुम्हारी सुणूंगा।"

करीब ४५ मिनट तक टिकैत से हमारी बात हुई। इस बीच भौरा कलां (सिसौली इसी क्षेत्र में आता है) के थानाध्यक्ष आर०एन० सिंह भी वहां आ गये। वह जाट थे। उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही टिकैत ने पूछा, "क्यों छुट्टी पर नहीं गये? तुम तो छुट्टी पर घर जानेवाले थे।"

"पुलिस की नौकरी में छुट्टी कहां है, चौधरी। फिर आपका इलाका भी तो देखना है। अफसर छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं", थानाध्यक्ष थोड़ा मायूस होकर बोला।

"जा छुट्टी चला जा। छुट्टी णा मिले, तो भी चला जा। मैं कप्ताण से कह दूंगा कि तू ड्यूटी पर रहा है। तेरी गैरहाजिरी में इस इलाके में परिन्दा पर भी नहीं मारेगा और सुण, तेरे सामणे महराज सिंह (शामली के ब्लाक प्रमुख) का मामला आवेगा। तू किसी के दबाव में मत आणा। न्याय की बात करणा। किसी के 'प्रेसर' में आया, तो अच्छा नहीं होगा।"

"चौधरी आप इत्मीनान रखो, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। न्याय की बात करूंगा और कोई हुक्म चौधरी।"

"नहीं, जा। ठीक से काम करना।"

थानाध्यक्ष ने ठीक वैसा ही सलाम ठोका, जैसे टिकैत उसके विभाग का कोई बड़ा अफसर हो। प्रस्तुत हैं, महेन्द्र सिंह टिकैत से 'माया' की बातचीत के अंश:

माया: आपने ११ अगस्त को मुख्यमंत्री को सिसौली बुलाकर बेइज्जत क्यों किया?

टिकैत: बेइज्जती उन्होंने खुद करायी। हमने नही की। वो हमारे मेहमान थे। जाते समय हमने उन्हें हलुवा खिलाया था। हमने सोचा था, हमारे बीच आकर वे हमारी बात करेंगे। इसीलिए हमने उन्हें अपना मंच दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने हठधर्मी की। इस इलाके को सूखा-क्षेत्र घोषित कर देते, तो उनका क्या बिगड़ जाता। हमारा प्रदेश हरियाणा से भी गरीब है। वहां की सरकार किसानों का कर्जा माफ कर सकती है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता है। फिर हमारी कोई मांग नही है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। मुझे मालूम है कि यह सरकार हमारा हक नहीं देगी, इसीलिए हमने १७ अक्टूबर को दिल्ली में ४० लाख किसानों की रैली बुलायी है। टिकैत ने बाद में घोषणा की कि वह यह रैली अब अगले वर्ष करेंगे।

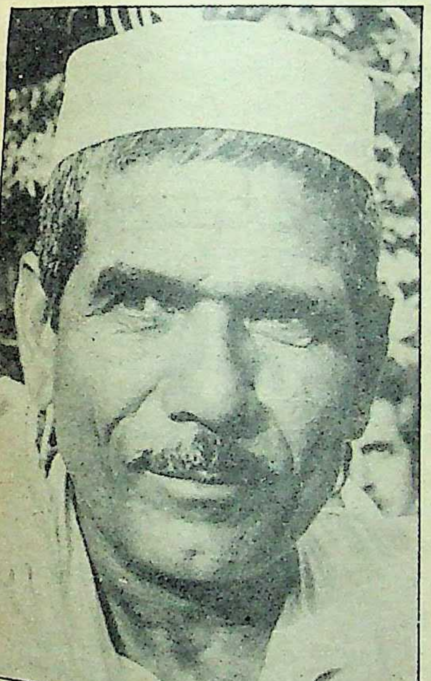

मैं सुनता आ रहा था कि राजा बहुत ईमानदार है। मैं मानता हूं, वह ईमानदार है, लेकिन दब्बू है। दब्बू न होता, तो जब पहली और दूसरी अप्रैल को मैंने उसे अपनी मीटिंग में बुलाया था, तो क्यों नहीं आया। मुझे दब्बू आदमी पर भरोसा नहीं है।

माया: आप कहते हैं कि आपकी यूनियन गैरराजनीतिक है, तो क्या चुनाव में आप किसी को 'सपोर्ट' (समर्थन) नहीं करेंगे?

टिकैत: हम अपने सभी लोगों से कहेंगे कि वोट जरूर डालो। सरकार किसी की बने हमारी यूनियन किसानों के हक के लिए लड़ती रहेगी, लेकिन हम किसी भी पार्टी को अपना मंच नहीं देंगे।

माया: राजा को भी नहीं?

टिकैत: नहीं। कतई नहीं।

माया: आखिर क्यों? इसके पहले तो आपने राजा को बुलाया था?

टिकैत: मैं सुनता आ रहा था कि राजा बहुत ईमानदार है। मैं मानता हूं, वह ईमानदार है लेकिन दब्बू है। दब्बू न होता, तो जब पहली और दूसरी अप्रैल को मैंने उसे अपनी मीटिंग में बुलाया था, तो क्यों नहीं आया। मुझे दब्बू आदमी पर भरोसा नहीं हैं।

माया: चरण सिंह के बारे में आपकी राय?

टिकैत: वह तो क़लयुग में अवतार थे। किसानों के भगवान थे।

माया: तो फिर उनकी पत्नी गायत्री देवी को आप महत्व क्यों नहीं देते हैं?

टिकैत: उसे भी महत्व देते हैं, लेकिन बस इतना कि वह चौधरी को ब्याही थी।

माया: और अजीत सिंह! एक तरह से तो वह आपके भगवान के पुत्र हुए। क्या आप उन्हें मदद नहीं करेंगे?

टिकैत: मदद तो परमात्मा करता है। मैं कौन होता हूं, मदद करनेवाला।

माया: मदद से मतलब चुनाव में सहयोग से है। अगर अजीत सिंह चुनाव में आपका आशीर्वाद लेने आयें, तो क्या नहीं देंगे?

टिकैत: मैं तो सिर पर हाथ फेर दूंगा। मदद यही करूंगा कि कह दूंगा-रोटी खाकर जा। राजा आयेगा, उसको भी रोटी खिलाऊंगा।

माया: अगर चुनाव से पहले राजीव गांधी किसानों को उनका 'हक' दे दें और आपसे कहें कि हमारी पार्टी को 'सपोर्ट' (समर्थन) करो तब आप क्या करेंगे?

टिकैत: उन्हें वोट नहीं देंगे।

माया: आखिर क्यों?

टिकैत: राजीव गांधी की सरकार जो कारनामें कर रही है, उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। हम सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। लगान नहीं दे रहे हैं। बिजली का पैसा नहीं दे रहे हैं और फिर चुनाव से पहले 'हक' नहीं 'लालच' दिया जाता है। हम लालच में आनेवाले नहीं हैं।

माया: अच्छा, अगर राजीव गांधी यहां आपसे बात करने आयें, तो आप उनसे बात करेंगे?

टिकैत: क्यों नहीं। पांडवों ने भी तो कौरवों से बात की थी। राजीव तो कौरवों का ही 'रोल' अदा कर रहे हैं।

किसान यूनियन के लोग श्रमदान से नहर खोद देंगे। सरकार का ७० लाख रुपए बच जायेगा। इसी तरह के दूसरे काम भी हम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। इसलिए कि अगर हम श्रमदान करेंगे, तो 'ऊपर' कमीशन कैसे पहुंचेगा। कमीशन के चक्कर में ही देश का बेड़ा गर्क हो रहा है।

माया: सब लोग यही कहते हैं कि अगर आप इस इलाके से चुनाव लड़ें, तो काफी वोटों से जीतेंगे।

टिकैत: मैं जानता हूं, मैं हार जाऊंगा। फिर मैं तो लड़ने का भी नहीं। मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है जो इलेक्शन लडूं। गिनकर चार रोटियां खाता हूं। मेरे को इलेक्शन-विलेक्शन नहीं लड़ना।

माया: आप अचानक ६ महीने के अन्दर किसानों के इतने बड़े नेता कैसे बन गये?
टिकैत: किसान बावलों (धुन के पक्के) की जमात है। उनकी भाषा मैं ही समझता हूं।

माया: जिस तरह आपने असहयोग आन्दोलन चलाया है, उसी तरह अगर व्यापारी यह कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे, छात्र कहें कि हम फीस नहीं देंगे, समाज के दूसरे वर्ग भी इसी तरह का असहयोग शुरू कर दें, तो सरकार कैसे चलेगी? किसान के काम कैसे होंगे?
टिकैत: सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। सब चल जायेगा। रही सरकार चलने की बात तो मैं कहता हूं कि यहां का जो पैसा लोगों ने विदेशों में जमा कर रखा है, सरकार उसे मंगवाती क्यों नहीं है। जब चौकीदार की ही नीयत खराब हो, तो चोर का क्या दोष।

माया: यूनियन के ही एक दूसरे नेता चौधरी सुखवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि आपने यूनियन के पैसों का दुरुपयोग किया है तथा खुद यूनियन के सर्वेसर्वा बन गये हैं।
टिकैत: सुखवीर सिंह, राजनीतिक लोगों के साथ है। इसीलिए हमारा उसका रास्ता अलग-अलग हो गया है। लेकिन यूनियन उसके बाप की नहीं है। जिसे किसान चाहेगा वही सर्वेसर्वा बनेगा। अब यह नहीं चलेगा कि एक कमरे में बैठकर जिसे चाहे अध्यक्ष बना दो। सुखवीर सिंह में हिम्मत हो, तो किसानों के बीच आकर यह बात कहे। यह सही है कि हम पुरानी किसान यूनियन का रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई कानूनी बात पड़ी, तो हम अपनी यूनियन का अलग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे।

माया: और चंदा खाने का आरोप...।
टिकैत: चंदा कोई हमने अपने पास नहीं रखा है। गांव का पैसा गांव में जमा है। सारा हिसाब हमारे पास है। हमें किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। यूनियन का दुरुपयोग हम नहीं, वो कर रहे हैं। वे लोग इसे राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं। मैं नहीं बनने दूंगा।

माया: सुखवीर सिंह ने कहा है कि वह आप पर मुकदमा करेंगे।
टिकैत: जो जी में आये करें। किसान ही उन्हें जवाब देगा। मैं तो बोलूंगा भी नहीं। जब तक हमारा मन होगा, हम रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल करते रहेंगे। जिसके साथ किसान है, वही असली यूनियन है। मेरी कोशिश है कि किसानों में इसी तरह का वातावरण पूरे देश में बने।

माया: आपकी नजर में देश के वर्तमान हालात कैसे ठीक हो सकते हैं?
टिकैत: राम का नाम जपने से सब ठीक हो जायेगा। वही एक ऐसी शक्ति है, उसे न मानने की वजह से ही बेड़ा गर्क हो रहा है। एक चीज और है-चरित्र। उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी नवयुवकों की है। चरित्र से बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि से ज्ञान आता है। ज्ञान से तत्व ज्ञान पैदा होता है। तत्व ज्ञान से विचार बनते हैं। विचार सही हो जायें, तो समाज सही हो जायेगा, देश सही हो जायेगा। आज, यह जो हिन्दू-मुसलमान लड़ रहे हैं, यह खुद नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाये जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के स्वार्थी लोग लड़वा रहे हैं। सरकार उन्हें हवा दे रही है, ताकि वे लड़ते रहें और असली मुद्दों से उनका ध्यान हटा रहे। यही वजह है कि शहर के हिन्दू-मुसलमानों में कोई तालमेल नहीं है। उनमें हया-शर्म नहीं है। देहात के लोगों में यह बात नहीं है।

राजीव गांधी की सरकार जो कारनामे कर रही है, उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। हम सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। लगान नहीं दे रहे हैं। बिजली का पैसा नहीं दे रहे हैं और फिर चुनाव से पहले 'हक' नहीं 'लालच' दिया जाता है।

माया: देश के हालात ठीक करने में सरकार की भी भूमिका रहती है। मुल्क में एक अच्छी सरकार रहे, इसके लिए चुनाव के मौके पर आप किसानों को किसी-न-किसी पार्टी को वोट देने का इशारा तो करेंगे ही?
टिकैत: मौके पर सब अपने आप समझ जायेंगे।

माया: राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अजीत सिंह में आप सबसे अच्छा किसे समझते हैं?
टिकैत: हो रही है न चालबाजी। फिर घुमा फिराकर वही सवाल। मैं इसका जवाब न देने का।

माया: लेकिन पहले तो आप कह चुके हैं कि राजीव कौरव हैं...।
टिकैत: तो ये भी तो कही है कि राजा दब्बू है। रही अजीत की बात तो मतलब तू निकाल लेना। उसके बारे में मैं यही कहूं, 'मां पर धीर, पिता पर घोड़ा, बहुत समझना थोड़ा-थोड़ा।'

माया: आप इतने कम समय में इतने बड़े नेता बन गये कि देश भर के तमाम अखबारों में आपकी फोटो छपी हैं। आपके दफ्तर में रखे रजिस्टर में कई बड़े-बड़े पत्रकारों के नाम लिखे हैं। पत्र-पत्रिकाओं में अपने चित्र देखकर आपको कैसा महसूस होता है।
टिकैत: मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगता। जैसे पहले किसान था, वैसा ही अब भी हूं। वही चार रोटियां खाता हूं, भले ही किसी को बुरी लगे। दूसरे नेताओं की तरह न तो दारू पीता हूं और न मांस खाता हूं। रूखी-सूखी खाता हूं। जमीन पर सोता हूं।

माया: कोई और बात कहना चाहेंगे।
टिकैत: हां भई। एक बात है। जी चाहे तो लिख देना। यह जो चौगामा (खापों के गांव) का इलाका है, इसमें नहर निकालने के लिए सरकार ने ७० लाख रुपए की योजना बनायी है। मैं कहता हूं कि सरकार केवल नहर निकलनेवाले स्थानों पर निशान लगा दे। किसान यूनियन के लोग श्रमदान से नहर खोद देंगे। सरकार का ७० लाख रुपए बच जायेगा। इसी तरह के दूसरे काम भी हम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। इसलिए कि अगर हम श्रमदान करेंगे, तो 'ऊपर' कमीशन कैसे पहुंचेगा। कमीशन के चक्कर में ही देश का बेड़ा गर्क हो रहा है।

—अजय कुमार

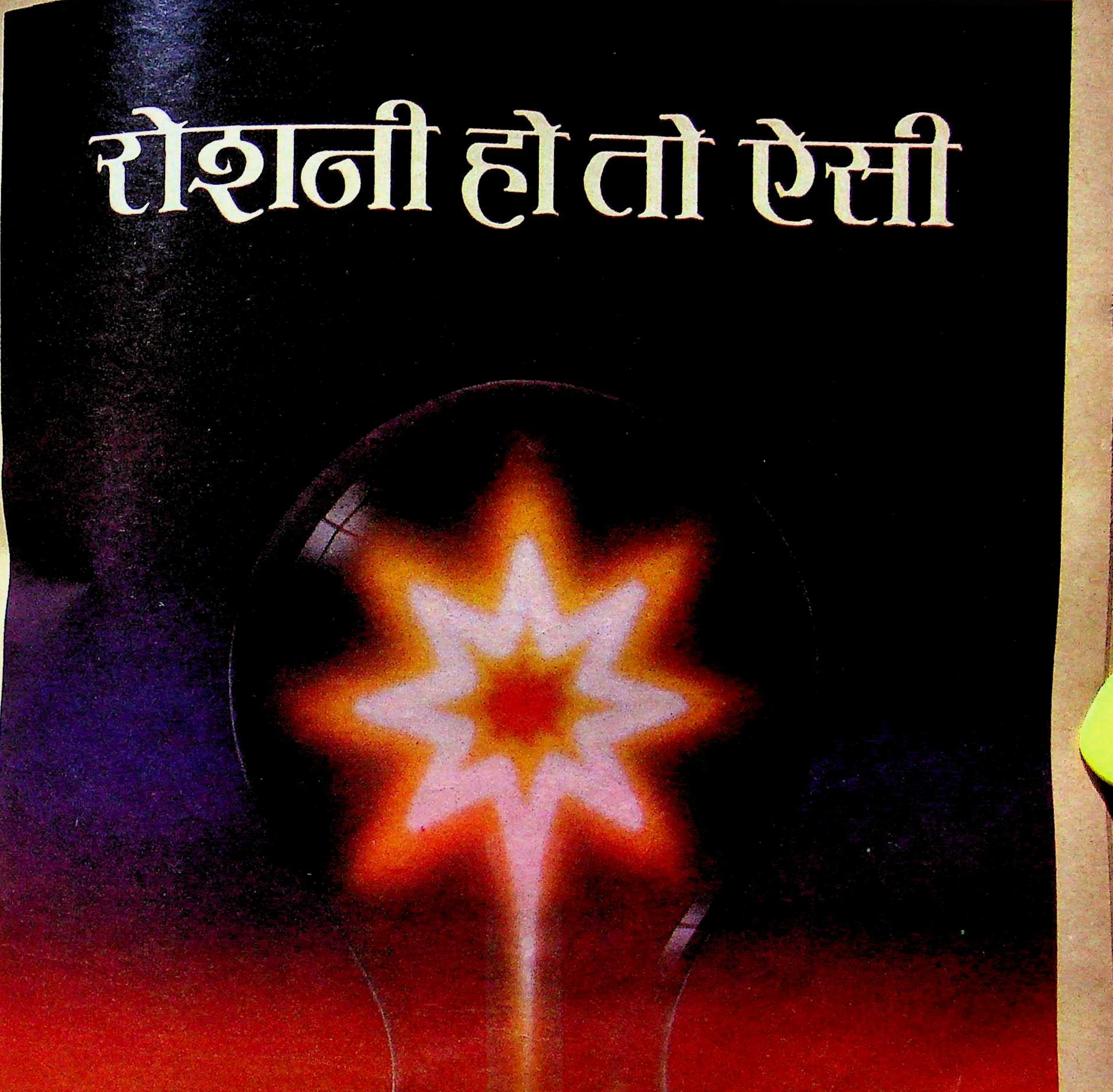

हर बजाज बल्ब का कांच-खोल पूरी तरह सीलबंद होता है ताकि वह ऊपरी टोपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहे. इसके कारण बल्ब के फटने या अचानक खराब हो जाने का कोई खतरा नहीं.

दरअसल हर बजाज बल्ब को क्वालिटी की सौ कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है जिसमें ऊपरी टोपी की मजबूती की जांच के लिए 'टॉर्शन-टेस्ट' भी शामिल है.

जब भी बल्बों की बात चलती है, उनकी क्वालिटी, मजबूती और विश्वसनीयता की एक ही गारंटी काफी है-बजाज का नाम.

bajaj group

बजाज बल्ब bajaj

कम ख़र्च में चलते ज़्यादा

Heros BE-869 HN

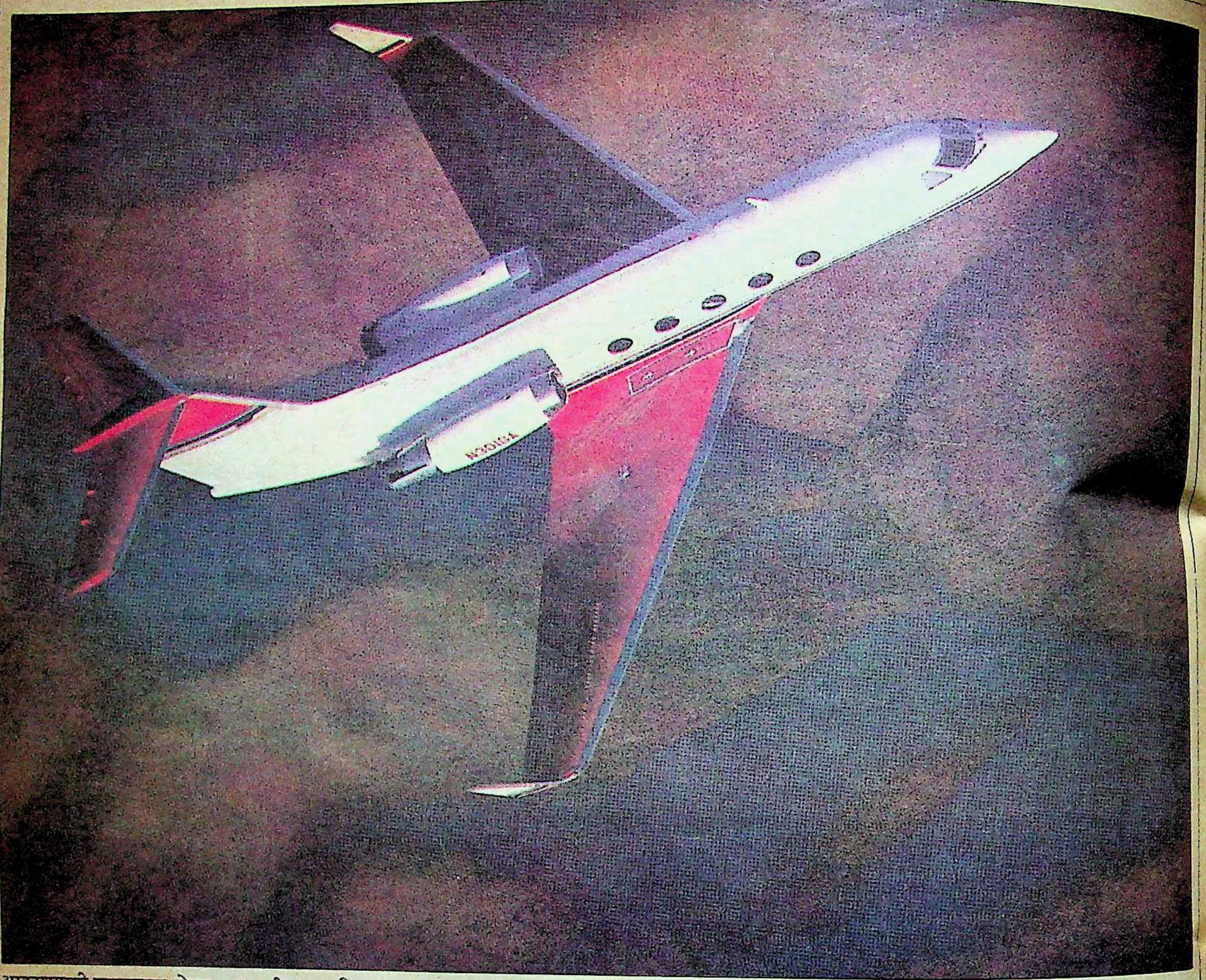

आकाशगामी फाइवस्टार होटल : गल्फस्ट्रीम—।।। विमान

गल्फस्ट्रीम विमान

विलासितापूर्ण विमान क्यों खरीदे गये ?

अमरीकी सरकार ने अपने खर्च में कटौती करने के लिए अपने ही देश की कंपनी गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस कारपोरेशन के वैभव-विलासिता से भरे जिन गल्फस्ट्रीम-।।। नामक हवाई जहाजों का आर्डर देकर खरीदने से इनकार कर दिया था, उन्हें इस सदी के भयानकतम सूखे का सामना कर रही भारत सरकार ने सत्ता पर बैठे विशेष लोगों की सुरक्षा के नाम पर २०-२० करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये वे विमान हैं, जिनका इस्तेमाल धनकुबेर किया करते हैं। हमारा विदेशी मुद्रा कोष एक-एक पैसे का मोहताज है, फिर भी विशिष्ट लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए इन विलासितापूर्ण विमानों का तत्काल खरीदा जाना क्या जरूरी था, जबकि पिछले तीन महीनों से इनका एक भी बार उपयोग नहीं हुआ ? क्या इस सौदे में भी सत्ता से जुड़े किसी खास आदमी ने दलाली खाकर देश को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है ?

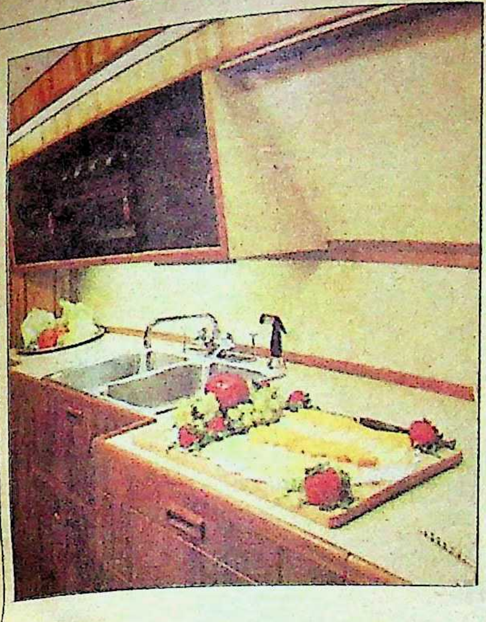

आलीशान खाना

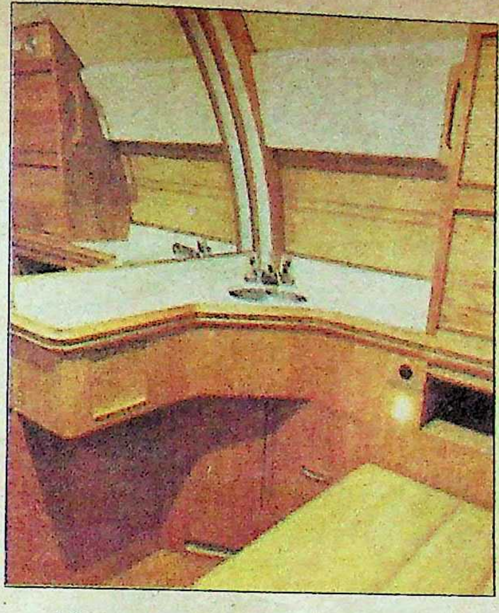

भव्य ड्रेसिंग रूम

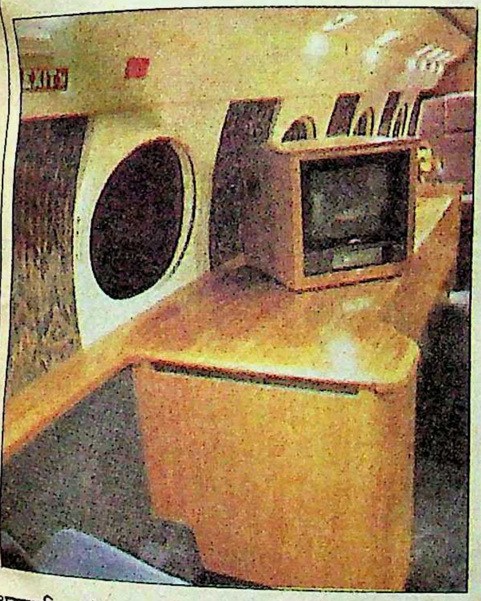

अत्याधुनिक संचार-साधन

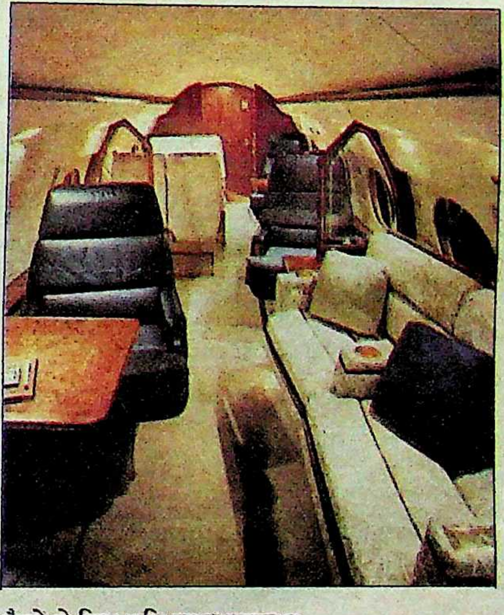

बैठने के लिए अति सुखद व्यवस्था

बिना रुके दिल्ली से जेनेवा अथवा रोम या लंदन से न्यूयार्क तक सीधी उड़ान भरने में समर्थ वैभव-विलासिता के भव्य उड़न-प्रासाद गल्फस्ट्रीम—III माडल के दो हवाई जहाज पालम एयर पोर्ट के हैंगर में महीनों से अपने उपयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख धनकुबेरों के निजी उपयोग में आनेवाले ये हवाई जहाज भारत सरकार द्वारा अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अमरीकी कम्पनी गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस कारपोरेशन, जार्जिया से खरीदे गये हैं।

गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस कारपोरेशन, गल्फस्ट्रीम—II का विकसित माडल १९८० में गल्फस्ट्रीम—III के नाम से दुनिया के सामने लेकर आयी। वैमानिक विलासिता की इस परंपरा की शुरुआत गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस ने १९५८ में एक्जीक्यूटिव यात्रियों के लिए बिना रुके तेज रफ्तार से ३६०० किलोमीटर दूरी तय करनेवाले गल्फस्ट्रीम—I वायुयान बनाकर की। एक दशक में २०० जहाज बेचकर कंपनी ने १९७० में इसका विकसित स्वरूप गल्फस्ट्रीम—II पेश किया। अगले दशक में इस माडल के २५० जहाजों को बनाने के बाद १९८० में इन्होंने गल्फस्ट्रीम—III बनाया। नयी तकनीक विकसित कर लेने और धनपतियों में प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार बनाने में सफल कंपनी अब गल्फस्ट्रीम-४ बना रही है, जो गल्फस्ट्रीम—III से लगभग १८०० किलोमीटर अधिक की सीधी उड़ान भर सकता है। पिछले तीनों माडल गल्फस्ट्रीम—I, II और III का उत्पादन कंपनी ने बिलकुल बंद कर दिया है। फिलहाल संयुक्त राज्य अमरीका और डेनमार्क सहित कई देश अपनी वायु सेना में गल्फस्ट्रीम—III का उपयोग कर रहे हैं। लगभग २० देशों ने अपने देशों के अधिकारियों की सेवा के लिए इसे चुना है।

एक समय विश्व के सबसे धनी व्यक्ति ओनासिस और पी एल ओ के प्रमुख यासर अराफात के अलावा अमरीका की प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्रिका फारचून की 'फारचून ५००' सूची में प्रकाशित विश्व की ५०० बड़ी कंपनियों में से २०० कंपनियों के पास ये जहाज हैं।

गल्फस्ट्रीम—III की सीढ़ियां चढ़ते वक्त पता नहीं चलता कि हम हवा में उड़नेवाले किसी राजप्रासाद में जा रहे हैं। मगर १४ यात्रियों को लेकर उड़ने वाले इस जहाज का दरवाजा पार करते ही दुनिया बदल जाती है। विशिष्ट लोगों के लिए इस विमान में ४ प्रथम श्रेणी की निहायत आरामदेह सीटें. एक कांफ्रेंस रूम, तीन सीटोंवाले सोफा-कम-बेड, टेलीविजन, लकड़ी के पार्टीशन, कैबिन से लगे एक बड़े गलियारे, ८ घंटे की यात्रा में खाना बनाने के लिए उच्च तापक्रम के ओपन और छोटे फ्रिज, और खाने का सामान गरम रखने के लिए पर्याप्त उपकरणों से सजे आधुनिकतम किचन की व्यवस्था है। इतना ही नहीं. अतिविशिष्ट मेहमानों के लिए निजी प्रसाधन कक्ष साथ ही रेडियो-टेलीविजन और टेलेक्स, टाइपराइटर व अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरणों से सुसज्जित 'गल्फस्ट्रीम' तमाम वायुयात्रायें कर चुके लोगों का भी मन मोह लेता है। इस भव्य यान के प्रसाधन में लगे नलों की टोंटियां और कई अन्य प्लेटें सोने की हैं।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत एवियेशन रिसर्च सेंटर नामक इकाई के नाम पर खरीदे गये ये जहाज उन ५ जहाजों में से हैं, जिन्हें आर्डर देने के बाद बजट में कटौती के कारण अमरीकी वायुसेना नहीं ले सकी थी। मगर भयानक सूखे से परेशान हमारे देश और सरकार ने ३ महीने पहले ही ४० करोड़ के इन दो जहाजों की डिलेवरी ली।

गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस ने इन फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए भारत स्थित अपने एजेंट जो कोजारिख को कहा कि वह इन जहाजों को बिकवाने की व्यवस्था करे। गल्फस्ट्रीम का बंबई स्थित विदेशी एजेंट पिछले ४० वर्षों से भारत में रह रहा है। जुहू में अपनी कंपनी इन्डामेर के जरिये वह पिछले ४० वर्षों से खरीद-फरोख्त का धंधा कर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय विशेषकर एअर इंडिया में उसकी पहुंच को देखकर उसे 'एयर इंडिया का बादशाह' भी कहा जाता है। जो कोजारिख १९७७ में संजय गांधी के संपर्क में आया। संजय गांधी ने इनसे दो छोटे विमान खरीदे जो क्रमश: जयपुर और लखनऊ में क्रैश (ध्वस्त) हो गये। इसके बावजूद पुराने एअर क्राफ्ट और अतिरिक्त पुर्जे खरीदने-बेचने का धंधा करनेवाला जो फलता-फूलता रहा। उसने फुसरतगंज रायबरेली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्य सरकारों को भी ६५ लाख रुपए के ६ किंग एअर सी-९० जहाज बेचे। हास्य-व्यंग्य में 'ईमानदार जो' के नाम से बुलाये जानेवाले जो ने एवियेशन रिसर्च सेंटर से एक किंग एअर सी-९० लेकर उद्योगपति बजाज को १४० प्रतिशत अधिक कीमत लेकर एक करोड़ बीस लाख में बेच दिया। इसके पूर्व पिछले वर्षों के दौरान जो ने उड़ीसा व मध्य प्रदेश सरकार तथा एवियेशन रिसर्च सेंटर का किंग एअर बी-२०० नामक ६ जहाज ३ करोड़ रुपए में बेच चुका था।

गल्फस्ट्रीम का संदेश पाते ही एअर इंडिया

GOLDEN'S
FLAIR
DELUXE FILTER
A flair for fun!

FLAIR
DELUXE FILTER

Add flair to your style

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

GOVAN/FDF-F/2A/87

का बादशाह जो सक्रिय हो उठा और अपने संबंधों और प्रभाव का उपयोग करते हुए अमरीकी एअर फोर्स द्वारा आर्डर देकर लौटाये गये ये जहाज सूची मूल्य पर भारत-सरकार को बेच दिये। सवाल है, ग्राहक द्वारा माल लेने से इनकार किये जाने के बाद खरीदे गये इन जहाजों पर भारत ने मूल्य में कमी कर व्यापारिक लाभ क्यों नहीं लिया ?

एक ओर तो विशिष्ट लोगों के नाम पर खरीदे गये इन जहाजों का अब तक ३०-४० घंटे से अधिक उपयोग नहीं हो सका है। दूसरी ओर अमरीका के ही फाल्कन, लियरजेट और कनाडा के चैलेन्जर आदि को नहीं लिया गया जो १४ से १६ करोड़ रुपए के बीच मिल सकते थे, और इस काम के लिए गल्फस्ट्रीम—III से किसी तरह कम उपयोगी नहीं थे।

गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस की परंपरा के मुताबिक इन जहाजों का बनना बंद होना पहले से ही तय था, क्योंकि इनको एक दशक तक बेचने के बीच उन्होंने और अधिक तेज, अधिक दूरी तक बिना रुके उड़नेवाला नया माडल गल्फस्ट्रीम-४ तैयार कर लिया था।

इन जहाजों में दो समस्यायें और भी हैं। एक तो हर एक सौ घंटे की उड़ान पूरी होने के बाद जहाज को सर्विसिग के लिए सिंगापुर जाना होगा। दूसरे ६०० घंटे की उड़ान के बाद जहाज को अमरीका स्थित वर्कशाप भेजना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि जहाज की सर्विसिग के लिए सिंगापुर और अमरीका भेजने का खर्च भारत को उठाना पड़ेगा। इसकी उड़ान पर भी कम खर्च नहीं है। ईंधन, तेल, रखरखाव और अन्य खर्चे मिलाकर इस पर एक घंटे की उड़ान का खर्च १४०४ अमरीकी डालर आयेगा, जबकि गल्फस्ट्रीम-४ और चैलेन्जर ६०१-३ए का प्रति घंटे का उड़ान खर्च क्रमशः १३५४ और १०४४ अमरीकी डालर ही होता है जो गल्फस्ट्रीम के खर्च से काफी कम है।

जहाजों की खरीद का कारण जहां एवियेशन रिसर्च सेंटर के मुताबिक विशिष्ट लोगों के उपयोग के लिए है, वहीं लोकसभा में १२ अगस्त को कांग्रेस—स के के०पी० उन्नीकृष्णन और १३ अगस्त को राज्यसभा में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा दिये गये उत्तर के मुताबिक ये जहाज देश की सुरक्षा के लिए हैं।

इतनी विसंगतियों के बावजूद मजे की बात यह है कि इन्हें खरीदनेवाली संस्था एवियेशन रिसर्च सेंटर कैबिनेट सचिव के अंतर्गत आनेवाली एक इकाई है। इसके पास भारत सरकार के गोपनीय फंड होते हैं। अपनी खरीदारी के लिए यह कोई सामान्य तरीका अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल, जहाज खरीदने के लिए तैयार किये प्रारूप में केवल तीन जहाजों का उल्लेख इस ढंग से किया गया, जिसे देखकर सहज ही गल्फस्ट्रीम-III को खरीदने की राय बन सके।

तैयार किये गये प्रारूप में गल्फस्ट्रीम-III, व ४ के अलावा कैनेडियन चैलेन्जर ६०१-३ए रखा गया। इस प्रारूप में गल्फस्ट्रीम-III से गल्फस्ट्रीम-४ जहाज के अंदर की जगह आरामदेह सुविधाओं, अधिक दूरी और उड़ान के कम खर्च के लिए बेहतर पाया गया। कैनेडियन चैलेन्जर ६०१-३ए इन सभी दृष्टियों से सर्वोत्तम था। अभी यह जहाज नवम्बर-दिसम्बर, १९८७ में मिल सकता था, जबकि गल्फस्ट्रीम-४, १९८९ के मध्य तक मिल सकने के संकेत थे।

किंतु, जो कोजारिख को तो गल्फस्ट्रीम—III ही बेचने थे, इसलिए संस्तुति करते समय जहां गल्फस्ट्रीम-III व ४ के एक-एक जहाज की कीमत क्रमशः १७,७६,३०० और १६,८९,७०० अमरीकी डालर लिखी गयी वहीं कैनेडियन चैलेन्जर के एक जहाज के बजाय दो जहाजों की कीमत २६,१५००० अमरीकी डालर लिखी गयी, ताकि प्रथम दृष्टि में कैनेडियन चैलेन्जर महंगा लगे और उसकी जगह गल्फस्ट्रीम—III खरीदने की स्वीकृति मिल सके। और हुआ भी यही। क्या एवियेशन रिसर्च सेंटर अपने गोपनीय फंड से खरीद-फरोख्त करने में नियमों का उल्लघंन कर सकता है ? क्या उसे राष्ट्रीय धन के इस दुरुपयोग के लिए कोई चुनौती नहीं दी जा सकती ?

—दिलीप कुमार

SAFI
साफ़ी
SAFI
हमदर्द
HTA-5048BH

मोहक त्वचा! साफ़ी त्वचा!

कील-मुहासे, फोड़े-फुंसियां तथा त्वचा के अन्य रोग रक्त में विकार के चिन्ह हैं। रक्त के विकार से स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में आपको साफ़ी के स्वास्थ्यदायक तत्वों की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

साइन्टिफ़िक रिसर्च ने भी सिद्ध कर दिया है कि साफ़ी एक हानि-रहित रक्तशोधक औषधि और कीटाणु-नाशक है, और यह त्वचा को साफ़ और सुन्दर बनाती है तथा अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है।

निःसंदेह, साफ़ी पचास वर्षों से अधिक समय से एक सुप्रसिद्ध रक्तशोधक औषधि है।

२४ अत्यावश्यक रक्तशोधक तत्वों और जड़ी-बूटियों का अनोखा मिश्रण

साफ़ी

रक्त को साफ़ करती है। त्वचा को निखारती है।

हिंसा पर उतारू विधायक

बिहार के अति संवेदनशील जिले जहानाबाद के विधायक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। आपराधिक राजनीति के गढ़ इस जिले में गत २२ सितंबर को दो विरोधी गुटों में जो खूनी मुठभेड़ हुई, वह विधायकों के मतभेद उजागर करने के लिए काफी हैं। इस घटना के बाद एक विधायक जेल में बंद है, तो दूसरा फरार। इस घटना से काबीना मंत्री रामाश्रय सिंह का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? —पूरे मामले की छानबीन 'माया' संवाददाता **विकास कुमार झा** *द्वारा :*

जनता शासनकाल में राज्यमंत्री रह चुके डा० रामजतन सिन्हा को आपातकाल के दौरान भी पुलिस से बचने के लिए इस तरह नहीं छिपना पड़ा था, जैसे कि अभी, जबकि वह जहानाबाद जिले के मख्दुमपुर क्षेत्र से इंका के विधायक हैं। पुलिस महानिदेशक के सख्त आदेश के बाद कि रामजतन को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाये, पुलिस बेचैनी से रामजतन के गांव पुरान (थाना करपी) से लेकर पटना स्थित उनके विधायक आवास ४२ ए, क्रांति मार्ग में बार-बार छापे मारती रही। रामजतन के गांव में उनके घर की कुर्की-जब्ती भी पुलिस ने ऐन उसी दिन की, जिस दिन रामजतन की मां का श्राद्ध था। पुलिस की गिरफ्तारी के भय से रामजतन अपनी मां के श्राद्ध में भी नहीं पहुंच सके। देर तक पुलिस रामजतन के गांव में मंडराती रही कि मां के श्राद्धकर्म के अवसर पर तो रामजतन आयेंगे ही और उन्हें तत्काल गिरफ्त में ले लिया जायेगा।

रामजतन बिहार की आपराधिक राजनीति के नये सितारे हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर जिस वाकिये को लेकर वह पुलिस से भागे-भागे फिर रहे थे, उससे लगता है कि जहानाबाद की सनसनी खेज राजनीति में अपना सिक्का जमाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। रामजतन एक अरसे तक पटना विश्वविद्यालय में व्याख्याता भी रह चुके हैं।

२२ सितंबर को बिहार आपराधिक राजनीति के अब एक मात्र जीवित सितारे अरवल के निर्दलीय विधायक सरदार कृष्णा सिंह को भी खत्म करने की कोशिश की गयी थी। रामजतन सिन्हा पर यही आरोप है कि उनके सशस्त्र जत्थे ने कृष्णा सिंह की हत्या करने के लिए मोर्चाबंदी की। फिर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलीं। सरदार और रामजतन गुट की इस मुठभेड़ की सूचना पाकर सी० आर०पी० जवानों का दल तुरंत पहुंच गया। दोनों गुटों की इस खूनी मुठभेड़ को रोकने के क्रम में ही सी०आर०पी० का एक जवान घनश्याम पाठक हमलावरों की गोली से जान गंवा बैठा। बस अब

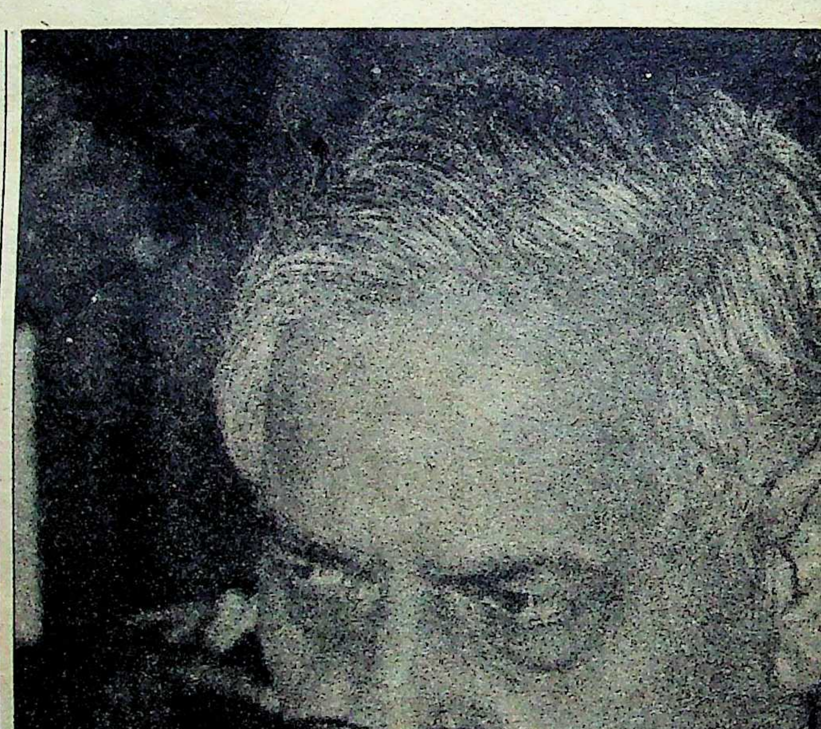

हिंसा को प्रश्रय : मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे

क्या था, उत्तेजित सी०आर०पी० के जवानों ने कहा कि अकेले हमारे जवान की लाश नहीं जायेगी, इन लोगों की लाशें भी अब साथ ही जायेंगी। देखते-देखते सी०आर०पी० की गोली से चार हमलावर वहीं मौत के घाट उतर गये। जहानाबाद के जिलाधिकारी हेमचंद्र सिरोही के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ तीस चक्र गोली चलायी, जबकि उस मुठभेड़ में हमलावरों ने सैकड़ों चक्र गोलियां चलायीं। बहरहाल, सरदार कृष्णा सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए भाग दौड़ शुरू की, पर रामजतन पकड़ में नहीं आ सके।

घटनाक्रम: आखिर निर्दलीय विधायक सरदार कृष्णा सिंह और रामजतन सिन्हा के बीच खूनी मुठभेड़ का कारण क्या था और यह हुआ कैसे? इस संबका खुलासा जहानाबाद के एस०डी०ओ० तेजनारायण लाल दास द्वारा जहानाबाद के तहत कुर्था थाने में २२ सितंबर को ही दर्ज करायी गयी प्राथमिक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में श्री दास ने लिखाया है, "२२ सितंबर को जब मैं भूमि विकास बैंक के चुनाव कार्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति जांचकर लगभग साढ़े बारह बजे अपने कार्यालय जहानाबाद पहुंचा तो वायरलेस द्वारा इसी समय अंचलाधिकारी कुर्था से सूचना मिली कि भूमि विकास बैंक के चुनाव को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। दोपहर के लगभग दो बजे कुर्था प्रखंड कार्यालय पहुंचने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुर्था तथा अंचलाधिकारी कुर्था ने बताया कि भूमि विकास बैंक का निर्वाचन, समझौते के आधार पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इसके पांच-सात मिनट बाद उत्तर-पश्चिम दिशा से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। तभी दस-पन्द्रह आदमियों ने आकर बताया कि सरदार कृष्णा सिंह को रामजतन सिन्हा तथा लगभग सौ-डेढ़ सौ हथियारबंद लोगों ने गंगहर नाला के नजदीक छेंक लिया है तथा उन पर लगातार गोलियों की बौछार की जा रही है। मैं आरक्षी उपाधीक्षक बी०एन० ओझा, आरक्षी निरीक्षक, कुर्था थाना के पुलिस पदाधिकारी, बी०एम०पी० तथा सी०आर०पी० एफ० के जवानों के साथ घटना स्थल की ओर दौड़ा। गंगहर नाले के नजदीक सैकड़ों आदमी नाले तथा खेतों की मेड़ पर पोजीशन लेकर लगातार गोलियां चला रहे थे। घटना स्थल पर पहुंचने पर आक्रमणकारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। आक्रमणकारियों की गोली से सी०आर०पी०एफ० का एक जवान घायल होकर मैदान में ही गिर गया। पुलिस फोर्स को आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का आदेश दिया गया। यह मुठभेड़ लगभग आधा घंटा चली। मुठभेड़ में चार आक्रमणकारी मारे गये। इन चारों के पास बंदूकें थीं। पुलिस द्वारा फायरिंग शुरू करने पर कुछ आक्रमणकारी जीप पर सवार होकर किंजर की ओर भाग गये। घटना स्थल पर मृतकों के पास से पायी गयी बंदूकों के अतिरिक्त भी बंदूकें, राइफल तथा कारतूस पाये गये, जिन्हें आक्रमणकारी छोड़कर भाग गयें थे। फायरिंग बंद होने के बाद सरदार कृष्णा, उनके भाई सुधीर कुमार तथा अंगरक्षक घायल अवस्था में पकड़ लिये गये। ये भी घटना के समय गोलियां चला रहे थे। आक्रमणकारियों द्वारा द०प्र०स० की धारा १४४ के तहत प्रचारित निषेधाज्ञा का उल्लघंन करते हुए संगीन अपराध किये गये हैं, अत: अविलंब कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।"

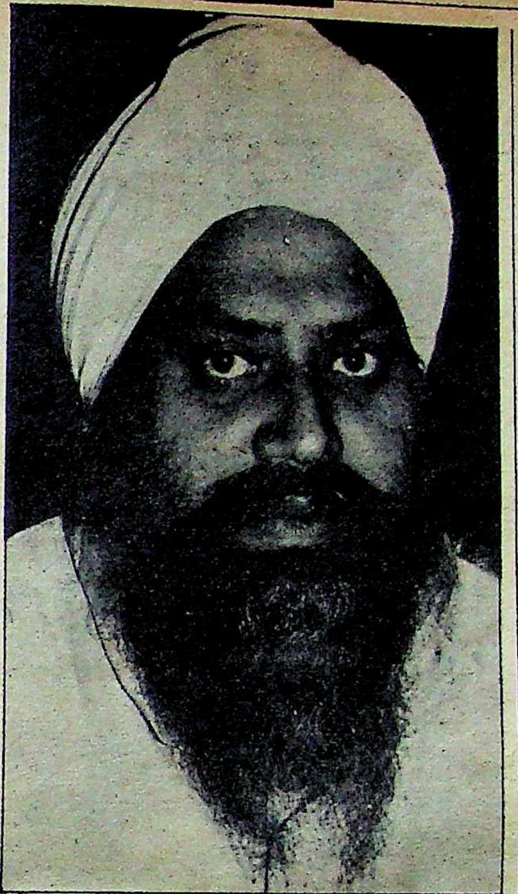
बाल-बाल बचे: निर्दलीय विधायक सरदार कृष्णा सिंह

बहरहाल, जहानाबाद के एस०डी०ओ० तेज नारायण लाल दास की इस प्राथमिक रिपोर्ट के अलावा दो और रिपोर्टें इस वारदात के सिलसिले में दर्ज करायी गयीं। एक सरदार कृष्णा सिंह की ओर से दूसरी रामजतन सिन्हा की ओर से। २२ सितंबर को ही दर्ज करायी अपनी रिपोर्ट में सरदार कृष्णा ने रामजतन सिन्हा के अतिरिक्त सौ से अधिक लोगों के नाम दिये हैं। श्री कृष्णा की प्राथमिकी के मुताबिक "करपी से कुर्था के रास्ते में रामजतन तथा उसके हथियारबंद जत्थे ने उनकी गाड़ी घेर कर फायरिंग शुरू कर दी थी। रामजतन की गोली से उनका भाई घायल हो गया और रामजतन के एक सहयोगी रवीन्द्र की गोली उनके पेट की ऊपरी सतह को छीलती हुई निकल गयी।"

२५ सितंबर को दर्ज करायी अपनी रिपोर्ट में रामजतन सिन्हा ने बिहार के सिंचाई मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह को भी लपेटा है। रामजतन की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विकास बैंक के चुनाव में अधिकांश सीटों पर उनके लोग प्रतिनिधि के रूप में जीत गये थे। कृष्णा सिंह उत्तेजित थे। चुनावी जायजा लेने वह कुर्था पहुंचे ही थे कि वहीं सूचना मिली कि उनकी मां आखिरी सांसें गिन रही हैं। बस तत्काल वह मृत्युशय्या पर पड़ी अपनी मां से मिलने पटना चल पड़े। कुर्था के पास ही निर्मल सिंह, के०डी० सिंह और जोगिंदर सिंह नामक तीन व्यक्तियों ने अचानक उनकी गाड़ी के सामने अपनी मोटर साइकिल अड़ा दी। ये लोग राइफल से लैस थे। इन लोगों ने कहा—आपने सरदार जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस कैसे किया? रिपोर्ट के अनुसार जोगिंदर सिंह ने सरदार कृष्णा काबीनामंत्री रामाश्रय सिंह के साथ पटना से अरवल होते हुए जहानाबाद गये हैं, लेकिन तभी अपनी गाड़ी पर अन्य हथियारबंद समर्थकों सहित सरदार कृष्णा पहुंचे गये। उन्होंने अपनी सशस्त्र टोली से चिल्लाकर कहा, "चलाओ गोली यह रामाश्रय बाबू के साथ-साथ मुझे भी तंग करता है। आज ही इसे ऊपर पहुंचा दो।" रिपोर्ट के अनुसार अगर उनके ड्राइवर ने गाड़ी तेज नहीं भगायी होती तो वे उनकी जान ले लेते।

बहरहाल, सरदार कृष्णा और रामजतन की रिपोर्टें तो महज भूमि विकास बैंक के प्रखंड स्तरीय चुनाव के दौरान उपजे तनाव को लेकर हैं, पर ये बिहार के सर्वाधिक संवेदनशील जहानाबाद जिले की खतरनाक इंकाई राजनीति की अंतर्कथा अपने आप में छिपाये हुए हैं।

पृष्ठभूमि: सी०आर०पी० जवान सहित पांच लोगों के मारे जाने की बात तो बहुत पहले ठंडी पड़ चुकी है, पर जहानाबाद के तमाम इंका विधायकों का खौफनाक मल्लयुद्ध नये सिरे से ताजा हो गया है। दरअसल, विगत संसदीय चुनाव के बाद से ही जहानाबाद की इंका राजनीति खतरनाक करवटें ले रही है। सबसे पहले तो जहानाबाद संसदीय चुनाव में इंका प्रत्याशी किंग महेन्द्र जब कम्युनिस्ट प्रत्याशी से चुनाव हार गये तो इंका के दिग्गज खिलाड़ी व जहानाबाद इंका के महंत माने जाने वाले बिहार के काबीना मंत्री रामाश्रय सिंह पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ही भितरघात कर किंग महेन्द्र को पराजित करवा दिया। माखन लाल फोतेदार के करीबी किंग महेन्द्र ने तय किया कि रामाश्रय से अपनी पराजय का बदला वह लेंगे। लोकसभा में पराजित किंग महेन्द्र ने तत्काल जोड़-तोड़ भिड़ाकर राज्य सभा की सदस्यता हासिल कर ली। इसके बाद आये विधानसभा के चुनाव। किंग महेन्द्र ने दिल्ली दरबार में अपने प्रभाव से जहानाबाद के तहत तमाम विधानसभाई सीटों पर रामाश्रय विरोधियों को टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जिताने में मदद की। साथ ही मख्दुमपुर विधानसभा क्षेत्र से रामाश्रय सिंह का टिकट कटवा कर रामजतन सिन्हा को इंका प्रत्याशी बनवा दिया। यह सब रामाश्रय सिंह के राजनीतिक पतन की कारगर शुरुआत थी। विधानसभा चुनाव में किंग महेन्द्र समर्थित इंका प्रत्याशी जहानाबाद से सैयद असगर हुसैन, घोसी से जगदीश शर्मा, मख्दुमपुर से रामजतन सिन्हा और बेलागंज से अभिराम शर्मा चुनाव जीत गये। इस तरह रामाश्रय

प्रसाद सिंह जहां एक झटके में विधानसभा के बाहर हो गये वहीं उनके तमाम विरोधी विधानसभा में एक मुश्त जा डटे। रामाश्रय सिंह के लिए भी जीवन-मरण का ही प्रश्न था। लिहाजा, दिल्ली दरबार में अहर्निश गुहार करके और मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दुबे को मिलाकर विधान परिषद में खुद के मनोनयन का उन्होंने इंतजाम कर ही लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दुबे की काबीना में वह मंत्री भी बनने में कामयाब हो गये। दरअसल, मुख्यमंत्री दुबे को भी रामाश्रय जैसे कुछ अनुभवी मंत्रियों की जरूरत थी क्योंकि पूर्व में गिरिडीह से सांसद रहने के कारण दुबे प्रांतीय राजनीति से कटे-हुए थे, लिहाजा सरकार चलाने के लिए उन्हें कुछ जानकार लोगों की दरकार थी। इस तरह दोबारा अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त करके रामाश्रय सिंह ने खुद को सरकार में स्थापित कर लिया और दुबे के भरोसेमंद मंत्रियों में गिने जाने लगे। रामाश्रय के हितैषी व विरोधी दोनों कहा करते हैं कि रामाश्रय सिंह बिलकुल टमाटर की तरह हैं जो हर सब्जी में आसानी से खप जाते हैं। यानी हर सरकार में हर मुख्यमंत्री के साथ उनकी गोट जम ही जाती है। दुबे के दरबार में इसी तरह अलख जगाते हुए रामाश्रय इस ताक में थे कि किसी सूरत में दोबारा उन्हें विधानसभा में पहुंचना है। इसी मुहिम के तहत कोंच क्षेत्र के उपचुनाव में दुबे के अनुग्रह से रामाश्रय चुनाव लड़कर विधान सभा में जा बैठे। अब रामाश्रय ने पूरी तौर पर अपनी खोयी शक्ति हासिल कर ली थी। इसके बाद जहानाबाद जिले के अपने विरोधी इंका विधायकों को मुंह की देने का सिलसिला शुरू हुआ। रामाश्रय ठहरे घाघ राजनीतिक, जबकि जगदीश शर्मा, रामजतन सिन्हा, अभिराम शर्मा या असगर हुसैन आदि सभी विधायक युवा थे, जो कि महीन राजनीति में उतने माहिर नहीं। लिहाजा, रामाश्रय के दांवों से इन सभी विधायकों की परेशानी रोजमर्रे के हिसाब से बढ़ती गयी। मख्दुमपुर जो रामाश्रय का पुराना क्षेत्र था, रामाश्रय ने वहां की राजनीति में अपनी गतिविधियां और तेज कर दीं। नतीजतन, मख्दुमपुर के विधायक रामजतन की परेशानी स्वाभाविक थी। जिले की राजनीति में इन तमाम विधायकों के विरोधी तेवर से रामाश्रय ने सबसे अलग-थलग पड़े अरवल के निर्दलीय विधायक सरदार कृष्णा सिंह से तालमेल बिठाया, ताकि इन सभी विरोधी विधायकों की लाबी से दो-चार हाथ किया जा सके। कुर्था के निर्दलीय विधायक नागमणि को भी रामाश्रय ने अपनी तरफ मिला लिया। अब बाकायदा हर कदम पर मोर्चाबंदी और मुठभेड़ शुरू हो गयी। इसी खतरनाक दौर का एक पड़ाव था, २२ सितंबर को कुर्था में भूमि विकास बैंक के ब्लाक स्तर का चुनाव। प्रतिनिधि के लिए काबीना मंत्री होने के बावजूद रामाश्रय भी लड़ गये। रामजतन और सरदार कृष्णा तो लड़े ही। रामजतन सिन्हा ने भी हर संभव तैयारी कर रखी थी। प्रतिनिधि के चुनाव में रामजतन बाजी मार ले गये और रामाश्रय तथा सरदार कृष्णा का गठबंधन मात खा गया। इसी उतार-चढ़ाव में कुर्था के पास अपना-अपना राजनीतिक जोर जताने के लिए सैकड़ों बंदूकों की 'ट्रिगर' दबी।

सरदार कृष्णा तो जेल जाने के आदी रहे हैं, सो गिरफ्तारी देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं हुई, पर मारधाड़ की राजनीति में नये-नये उभरे रामजतन सिन्हा को जेल जाना आसानी से कबूल नहीं हुआ इसलिए वह फरार होकर छिपते फिर रहे हैं। भूमिगत अवस्था में ही एक मुलाकात में रामजतन सिन्हा ने 'माया' को बताया, "रामाश्रय सिंह की साजिश और मुख्यमंत्री की शह पर मेरी हत्या का निरंतर प्रयास जारी है। मुझे आशंका है कि जेल में ही मेरी हत्या की जा सकती है। २१ सितंबर की रात ही पालीगंज में सरदार कृष्णा और उसके गिरोह के साथ रामाश्रय सिंह ने गुप्त बैठक कर मेरी हत्या का षड्यंत्र किया। भूमि विकास बैंक में हमारे लोगों की भारी जीत से वह और भी बौखला उठे। पुलिस महानिदेशक भी रामाश्रय की शह पर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, पर मैं कानून का सम्मान करता हूं। कानून के रक्षार्थ मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। मैंने तो इन हादसों की लिखित आशंका बिहार के तमाम आला अफसरों को पहले ही दे दी थी। अगर उस पर कार्रवाई होती तो आज यह स्थिति नहीं होती।" जबकि जेल में बंद सरदार कृष्णा सिंह का कहना है, "पुलिस अगर ऐन वक्त पर न आ जाती तो रामजतन मेरी जान ले ही बैठे थे।"

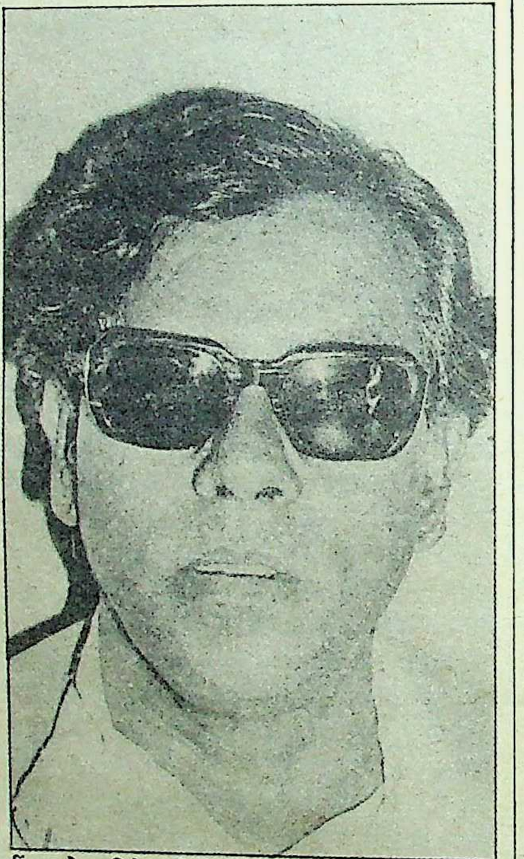
हिंसा के जरिये वर्चस्व : सिंचाई मंत्री रामाश्रय सिंह

प्रतिक्रियाएं : रामजतन बनाम सरदार कृष्णा कांड पर जहानाबाद के अधिकांश विधायक रामजतन के पक्ष में मुखर हैं। जहानाबाद के इंका विधायक सैयद असगर हुसैन कहते हैं, "जिले के हम तमाम युवा तुर्क विधायक जिले के कल्याण के लिए एकजुट होकर रहते हैं। यह बात रामाश्रय सिंह को खलती रहती है। जहानाबाद विधानसभाई क्षेत्र से १९६७ के बाद कभी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता था।

दरअसल, रामाश्रय सिंह हरदम इसी अभियान में रहे कि उनको छोड़कर कोई दूसरा कांग्रेसी इस इलाके से नहीं जीते। पर १९८५ में हम जैसे गैर-सामंती मध्यमवर्गीय परिवार के लड़के जब जीत कर विधानसभा में आये तो, उनका दुख दूना हो गया। अब सरदार कृष्णा का सहारा लेकर वह रामजतन सिन्हा के पीछे पड़े हैं। रामाश्रय को एक बात हरदम सालती है कि मख्दुमपुर तो उनका क्षेत्र था, वहां से रामजतन विधायक क्यों हैं? सरदार कृष्णा आज उनके मित्र हैं, पर इसी सरदार को गुजरे बर्षों में रामाश्रय सिंह ने ही कई बार जेल भिजवाया था। जहानाबाद के हम सभी युवा विधायक आलाकमान के पास इन बातों को रखने जा रहे हैं, क्योंकि रामाश्रय सिंह मुख्यमंत्री के नियंत्रण से भी बाहर हैं।"

बेलागंज के इंका विधायक अभिराम शर्मा कहते हैं, "रामाश्रय सिंह अगर अपने प्रयास में सफल हो गये होते, तो मैं आज विधायक ही नहीं होता। १९८० में जब पहली बार मुझे कांग्रेस का टिकट मिला था तो अपने रिश्तेदार कुमार कत्था फैक्ट्री के कृष्ण कुमार सिंह को चुनाव में मेरे खिलाफ लड़वा कर उन्होंने मुझे हराने में सफलता हासिल की, पर १९८५ में उनके सारे प्रयास विफल रहे और मैं जीत गया। जाहिर है कांग्रेस से इन्हें कोई हमदर्दी नहीं।

रामजतन और सरदार कृष्णा के बीच उभरे विवादों को लेकर रामाश्रय प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक रूप से आरोपों को निराधार बताया है। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री दुबे की नजर भी उन पर टेढ़ी चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या को लेकर उठे आरोपों के बाद मुख्यमंत्री दुबे ने सिंहभूम जिला बीस सूत्री के संयोजक से भी रामाश्रय सिंह को अपदस्थ कर दिया। अब नये सिरे से जहानाबाद के जंग की मुनादी हुई है, तो देखना है बाजी किसके हाथ लगती है। इन विवादों के दौरान किंग महेन्द्र विदेश यात्रा पर थे। तय है तेजी से यह जंग अपना रंग पकड़ेगी। पर इंका के एक मंजे नेता कहते हैं कि रामाश्रय विरोधी विधायकों की लाबी अपरिपक्वता के कारण मुख्यमंत्री दुबे का अनुग्रह पाने में विफल है। दुबे, चूंकि रामाश्रय से भीतर-भीतर कुढ़े रहते हैं, इसलिए मात्र हल्के प्रयास से इन सबों को दुबे का आशीर्वाद मिल जाता। रामजतन का यह आरोप कि दुबे की शह पर रामाश्रय साजिश कर रहे हैं, चाहे-अनचाहे रामाश्रय की मदद कर गया है। रामाश्रय ऐसे वक्तव्यों का राजनीतिक लाभ उठाना जानते हैं। असली राजनीति भी तो यही है, जिसमें अपने विरोधियों के बयान से घाटा उठाने की बजाय दोहरा फायदा उठाया जाता है।

—विकास कुमार झा

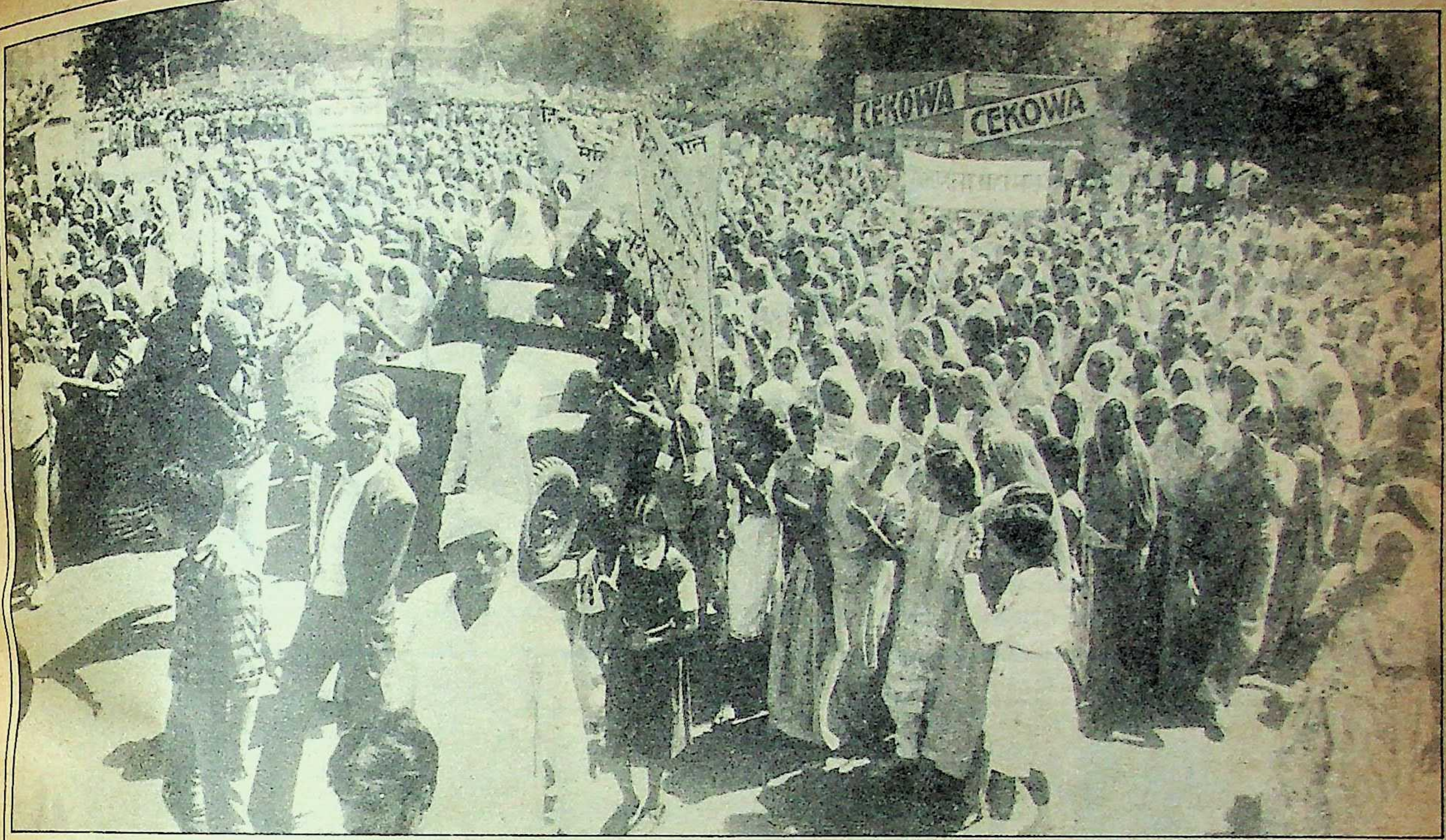

अपराध का आध्यात्मीकरण : सती के पक्ष में जुटी गुमराह भीड़

दिवराला : सती कांड के बाद

राजनेताओं की भूमिका

सती जैसी जघन्य घटना और फिर उसे महिमामंडिंत करने के विभिन्न आयोजनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में केवल राजस्थान सरकार ही हीला-हवाली नहीं कर रही है, बल्कि विभिन्न दलों के प्रांतीय नेता भी खुलकर समर्थन करने में लगे हैं। उनको डर है कि ऐसानकरने से उनको धर्मांध और एक जाति विशेष के वोटों से वंचित होना पड़ सकता है। सती की घटना ने जो तूल पकड़ा है, उसके पीछे राजनेताओं की भूमिका का जायजा—ओम सैनी द्वारा :

समाज जाये भाड़ में, वोटों पर आंच नहीं आनी चाहिए—आज की भारतीय राजनीति का यही 'आदर्श वाक्य' है। दिवराला के सती कांड के प्रति विभिन्न दलों के प्रांतीय नेताओं और सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे यह बात और उजागर हो गयी है। क्योंकि दुर्भाग्य से माहौल ऐसा बना है कि यह सती कांड एक जाति विशेष को गोलबंद करने का मुद्दा बन गया है, इसलिए कोई राजनेता यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि खुलकर इस कांड का विरोध कर सके। यहां तक कि महिला मंत्रियों और पक्ष-विपक्ष की महिला विधायकों ने भी चुप्पी साधने में ही अपना राजनीतिक हित समझा है।

सरकार की निष्क्रियता का आलम तो यह है कि रूपकंवर ४ सितंबर को जली और सती-शाप से भयभीत मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को इसे जघन्य अपराध कहने में ग्यारह दिन लगे। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद १६ सितंबर को तथाकथित 'चूंदड़ी समारोह' में एक लाख लोग पहुंच गये। सूत्रों के अनुसार 'चूंदड़ी समारोह' से पूर्व राज्य मंत्रिमंडल की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, जिसमें ज्यादातर मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में दखल न देने की राय जाहिर की थी। इन मंत्रियों का तर्क था कि सरकार सतियों को सम्मान देती रही है। उनके मंदिरों में मंत्री सिर झुकाते हैं। वहां लगने वाले मेलों में सरकारी विभाग मंडप लगाते हैं। झुंझुनू जिले की राणी सती के मेले के दिन जिला प्रशासन छुट्टी रखता है। जब पहले से सतियों को महिमामंडित करने की मानसिकता चली आ रही है, तो अंधकारमय भविष्य से भयभीत रूपकंवर के जल मरने को महान त्याग की संज्ञा देकर मनाये जाने वाले जश्न को कैसे रोका जा सकता था? बताया जाता है कि ११ बजे के बजाय सुबह पौने आठ बजे ही 'चूंदड़ी समारोह' आयोजित करने में सरकारी मिलीभगत थी, जिससे सरकार उच्च न्यायालय की अवमानना के अपराध से बचने में सफल हो सके।

बहरहाल 'चूंदड़ी समारोह' के बाद सती प्रकरण की राष्ट्रव्यापी निंदा हुई और दिल्ली से टेलीफोन बजे, तो मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी अचानक घोर सती-विरोधी हो गये। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया। दिवराला में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। १९ सितंबर को अचानक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पी० चिदंबरम जयपुर आये। लेकिन इस बीच दिवराला में हुई गिरफ्तारियों और रूपकंवर के सती होने की आलोचना के विरोध में राजपूत समुदाय ने अपने को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। रियासतें और जागीरें खत्म होने के बाद जो राजपूत युवा नेताओं

का रुतबा हासिल कर चुके थे, वे इस मौके पर फिर से अपनी पुरानी तलवारों को चमकाते नजर आये। जयपुर के राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज के तथाकथित प्रमुख लोगों ने चिदंबरम के आगमन के दिन सभा की और फिर लगभग एक हजार लोग नंगी तलवारों व लाठियों से लैस होकर मंत्रियों की कालोनी-सिविल लाइंस में प्रदर्शन करने जा पहुंचे। इस प्रदर्शन का गौरतलब पहलू यह था कि जब चिदम्बरम के आगमन से पूर्व सती समर्थक खामोश थे, तो फिर प्रदर्शन का आयोजन किसके इशारे पर हुआ? राजपूत सभा भवन की सभा में राजपूत नेताओं ने सीकर के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के तबादले पर विशेष रूप से क्यों रोष प्रकट किया? मंत्रियों के आवास पर निहत्थे लोग भी प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, तो सुरक्षा के लिए नियुक्त आर०ए०सी० के सिपाही डंडे चलाने में नहीं हिचकते तो तलवारों से लैस लोग सुविधा से प्रदर्शन करते सिविल लाइंस में कैसे प्रवेश कर गये? निश्चित रूप से गृह विभाग के प्रमुख मंत्री गुलाब

स्वार्थ की राजनीति: सती स्थल पर कल्याण सिंह कालवी (घड़ी बांधे) अपने समर्थकों के साथ

साक्षात्कार/
कल्याण सिंह
कालवी

मंदिर बनाने पर रोक लगाना मूर्खतापूर्ण है

'माया' ने दिवराला सती काण्ड के समर्थक कहे जाने वाले जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी से लम्बी वार्ता की। वार्ता में लगा कि कालवी सती-समर्थक तो नहीं हैं, पर सती इतिहास को बड़े गर्व के साथ देखते हैं। उन्हें अपनी मार्शल कौम पर भी बड़ा नाज है। उनके गर्वीले इतिहास पर जब कोई उंगली उठाता है, तो वह अपना आपा खो बैठते हैं और लगता है जैसे वह आज भी सती-समर्थक हैं। प्रस्तुत हैं, वार्ता के कुछ अंश:

माया: कहा जाता है कि आप सती-प्रथा के समर्थक हैं?

कालवी: यह मुझे बदनाम करने का प्रयास है। मैं न कभी सती प्रथा-समर्थक था, न हूं और न रहूंगा। दरअसल रूपकंवर सती काण्ड को उछालने के लिए केन्द्र सरकार दोषी है। वह देश और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसे तूल दे रही है।

माया: पर आप तो दिवराला की आम सभा में घोषणा करके आये हैं कि सती-स्थल पर सरकारी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

कालवी: देखिए जो सरकार को सती होने से पहले करना चाहिए था, वह सरकार अब कर रही है। निर्दोष लोगों को तंग किया जा रहा है। इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। फिर कानून की दृष्टि से देखें, तो रूपकंवर ने आत्महत्या का अपराध जरूर किया है, पर उसके मरने के बाद अनुष्ठानों या छतरी और मन्दिर बनाने पर रोक लगाने की सरकारी कोशिश मूर्खतापूर्ण है। ऐसे में मेरा कहना गलत है क्या?

माया: आप मान रहे हैं कि रूपकंवर ने आत्महत्या का अपराध किया फिर अपराधी को कैसे महिमामंडित किया जा सकता है?

कालवी: क्यों? फांसी की सजा पाये मुजरिम के परिजन अन्तिम संस्कार में कोई कमी छोड़ते हैं क्या? फिर रूपकंवर का मामला हमारे इतिहास से जुड़ा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। ऐसे में यदि मन्दिर बनता है, तो सरकार को क्या एतराज है? भावनाओं को न तो लाठी के जोर से बदला जा सकता है और न कानून से। यह तो लोगों को ज्ञान और विवेक से ही समझाया जा सकता है।

माया: आप सती प्रथा को धर्मानुसार मानते हैं?

कालवी: इस पर टिप्पणीं करने का काम धर्मगुरुओं का है। वे आज इस सम्बध में जो कह रहे हैं, आप स्वयं देख लें।

माया: आरोप है कि आप राजपूतों को भड़का रहे हैं?

कालवी: क्या मेरा राजपूत होना गुनाह है? दिवराला में मेरे कई रिश्तेदार रहते हैं। उनके सुख-दुख में शामिल होना अपराध है। लोगों की भावनाओं से प्रेस और सरकार को अवगत कराना गुनाहं है? मैंने यही तो किया है, लोगों की भावनाओं से सबको अवगत कराया है।

माया: धर्म रक्षा समिति में आपका शामिल होना क्या आपकी पार्टी का निर्णय है?

कालवी: नहीं, यह निर्णय मेरा अपना है। पार्टी समुदायों से मिल कर बनती है। हमें हर समुदाय के बारे में ख्याल रखना होता है। ऐसे में मेरी पार्टी को कैसे एतराज होगा। रही बात अनुमति की वह किससे लें? सारे लोग ही तो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।

माया: नंगी तलवारों के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे?

कालवी: यह हमारा अपना कल्चर है, सिम्बल है। इसे गलत मत समझिए। सरकार जिस तरह लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, उसमें नंगी तलवारों का प्रदर्शन हो सकता है। सरकार प्रचारित कर रही है कि रूपकंवर को जबरन आग में झोंका गया। यह भी छपवाया जा रहा है कि रूपकंवर पथभ्रष्ट थी। ऐसे में मार्शल कौम क्या करेगी?

माया: सती प्रथा-विरोधी अध्यादेश जारी होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

कालवी: अभी इसे पढ़ रहा हूं। वैसे सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसे अध्यादेश जारी करती है। विधानसभा सत्र क्यों स्थगित किया सरकार ने? वहीं बात हो जाती अध्यादेश पर, मगर सरकार नहीं चाहती। फिर जागरूक लोग न्यायालयों में जवाब तलब कर रहे हैं, सरकार के लिए मुश्किल हो जायेगा जवाब देना।

—ओम सैनी

सिंह शक्तावत की शह के बगैर जंग लगी तलवारों का नंगा प्रदर्शन सिविल लाइंस में नहीं हो सकता था और शक्तावत की शख्सीयत ऐसी नहीं है जो मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की मर्जी के बगैर कुछ कर जाये।

चिदम्बरम से राजपूत नेताओं का शिष्ट मण्डल भी मिला, जिन्हें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कानून अपनी गति से चलेगा और उसकें तहत कार्यवाही'की जायेगी। उनके बयान से स्पष्ट हो रहा था कि वह मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन को सती काण्ड का दोषी मान रहे थे। इससे उबरने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संगठन के उन नेताओं के बयान अपने पक्ष में जुटाने शुरू कर दिये, जिन्हें प्रधानमंत्री के नजदीक समझा जाता है। मसलन मुख्यमंत्री ने २१ सितम्बर को अखिल भारतीय युवक कांग्रेस इ के तत्कालीन अध्यक्ष सांसद आनन्द शर्मा के जयपुर आने पर विशेष स्वागत सत्कार का इंतजाम किया। शर्मा अकाल पीड़ितों के लिए पंजाब, दिल्ली और गंगानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया इकत्तीस सौ बोरी गेहूं मुख्यमंत्री को भेंट करने आये थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा वक्त देते हुए सरकारी हवाई जहाज में प्रान्त की यात्रा करवायी। सांसद शर्मा ने मुख्यमंत्री को भीषण अकाल में बेहतर काम का प्रमाण-पत्र अपने बयान द्वारा ज़ारी कर दिया। 'माया' ने शर्मा से जानना चाहा कि क्या दिवराला की घटना और नंगी' तलवारों के जुलूस का कोई जवाब उनके प्रान्तीय संगठन के पास है? जवाब में सोने-चांदी की नगीनों से सजी पांच अंगूठियां धारण किये हुए अध्यक्ष ने अंगुलियां नचाते हुए फरमा दिया कि "अभी हम अकाल पीड़ित लोगों की मदद में लगे हैं।"

विरोध के स्वर, लेकिन बेअसर : सती विरोधी प्रदर्शन

२३ सितम्बर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी न. चन्द्र चतुर्वेदी अकाल राहत कार्यों का जायजा लेने राजस्थान आये। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी हेलीकाप्टर में ऐसा घुमाया कि पुष्कर के पास अकाल राहत के तहत काम करती महिलाओं से जब उन्होंने पूछा कि यहां कोई भूख से तो नहीं मरा, तो महिला श्रमिकों ने जवाब दिया, "म्हे तो भूखा मर रयां हां"—यानी हम तो भूखों मर रही है। पर चतुर्वेदी ने जाने से पहले अनुभवी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई दे दी। यही नहीं सती प्रकरण में भी चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री की मजबूरी वाले बयान का समर्थन करते हुए दिल्ली जाकर बयान दिया कि गृह राज्यमंत्री पी॰ चिदम्बरम जब जयपुर में थे, तो एक हजार राजपूत युवक नंगी तलवारें लेकर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। उन्होंने आगे फरमाया— "राजपूतों की भावना का पता इसी से लगता है कि चिदम्बरम वहां इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सके और उन्होंने दिल्ली आकर बयान दिया।" प्रभारी महासचिव से ऐसा प्रमाण पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री अपनी कुरसी के लिए आश्वस्त हो गये।

उधर प्रदेश युवक कांग्रेस इ के अध्यक्ष के॰सी॰ विश्नोई से जब 'माया' ने सती प्रकरण पर उनकी प्रतिक्रिया और कार्यक्रम जानना चाहा, तो उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री हमें कोई आदेश दें, तो हम कुछ करें और फिर करें भी क्या? कुछ करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा इसलिए चुप हैं।" प्रदेश कांग्रेस संगठन के नेता और असंतुष्ट कांग्रेसी सारे प्रकरण में मौन रहे हैं, पर जैसे ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सती प्रकरण में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी, तो सारे नेता बयानों के माध्यम से सक्रिय हो गये।

विपक्ष का रोल : राजस्थान के विपक्षी दल भी सती कांड में ज्यादा मुखर नहीं रहे। मसलन लोकदल ब की प्रांतीय शाखा ने इस मामले में चुप्पी धारण कर रखी है, जबकि लोकदल-अ के प्रदेश अध्यक्ष दौलतराम सारण सहित सभी नेताओं ने इसकी खुलकर आलोचना की। जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी ने सती प्रथा का विरोध करते हुए रूपकंवर की मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों पर रोक लगाने पर एतराज किया, जबकि इसी दल के माणक सुराणा ने इस रुख पर एतराज करते हुए उन्हें दल से निकालने की मांग शुरू कर दी। भाकपा और माकपा की प्रांतीय शाखाओं ने विरोध में बयान जारी कर संतोष कर लिया। हालांकि भाकपा के युवक संगठनों ने डेढ़ सौ युवकों की रैली इसके विरोध में जयपुर शहर में अवश्य निकाली। विपक्षी दलों में सबसे हास्यास्पद स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही। यह पार्टी अपने नेता भैरोंसिंह शेखावत की अनुपस्थिति में कुछ तय नहीं कर पायी। प्रांतीय अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा ने सती काण्ड को परम्परा का नाम देते हुए समर्थन दिया। वहीं २० सितम्बर को भाजपा नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने जयपुर में भाषण देते हुए प्रदेश भाजपा के रुख को गलत बताया। उन्होंने कहा कि रूपकंवर का जल मरना एक सामाजिक बुराई है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं।

बहरहाल दल-बल साबित करने के लिए जिस तरह से पक्ष-विपक्ष के नेता भीड़ जुटाकर राजधानी ले आते हैं, दिवराला में रूपकंवर के सती होने के विरोधं में ऐसा आयोजन किसी भी दल ने नहीं किया। फिर भी सती प्रकरण के विरोध और समर्थन का सबसे ज्यादा असर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के बाद जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह क़ालवी के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा।

प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी राजपूत समुदाय के पहले ऐसे नेता रहे, जिन्होंने २७ सितम्बर को दिवराला गांव में तथा कथित 'सती स्थंल' पर सभा आयोजित कर राजपूतों का संघर्ष के लिए आह्वान किया।

कालवी ने जब देखा कि उनके प्रयासों का विरोध जनता पार्टी के पदाधिकारी और गैर राजपूत विधायक करने लगे हैं, तो उन्होंने 'सती धर्म रक्षा समिति' का गठन करवाया। स्वयं समिति के सदस्य रहे, जबकि नरेन्द्र सिंह राजावत नामक एक युवक को उसका संयोजक बनाया। इस समिति ने २९ सितम्बर को राज्य विधान सभा सत्र शुरू होने से पहले संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें संयोजक चुप रहे और कालवी खूब बोले। कालवी का कहना था कि समिति के सभी सदस्य सती प्रथा के खिलाफ हैं, पर सती होने के बाद हिन्दू संस्कार और उनकी मान्यताओं में विघ्न डालना बर्दाश्त नहीं किया जायेगा (देखिए साक्षात्कार)। यहीं इन लोगों ने आठ अक्तूबर को उक्त मान्यता के समर्थक लोगों का जयपुर में सम्मेलन व प्रदर्शन भी आयोजित करने की घोषणा की।

इस बीच जयपुर का राजपूत छात्रावास नंगी तलवारों और मशाल जुलूसों के आयोजन में सक्रिय रहा। इसमें दिलचस्प तथ्य यह रहा कि प्रदर्शनकारियों से ज्यादा संख्या उन तमाशबीनों की

एक अशुभ संकेत

आठ अक्तूबर को जयपुर में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और उनके प्रशासन का मंजाक उड़ाते एक लाख लोगों के सती-समर्थक प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि वह साढ़े तीन करोड़ की जनसंख्या वाले राजस्थान की कुप्रथाओं और परम्पराओं को जीने के लिए बाध्य करेंगे। इस प्रदर्शन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान में राजपूत राजनीति के संचालन का अधिकार केवल प्रान्तीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी को है। अब तक समझा जाता था कि राजपूतों को इधर या उधर ले जाना राजा-महाराजाओं के बाद भाजपा के नेता भैरोंसिह शेखावत के बस की बात है।

जयपुर के रामलीला मैदान में 'धर्म रक्षा समिति' के आह्वान पर चार घंटे तक चली यह सभा ऐसी सभा थी, जिसमें हिन्दुओं का केवल एक वर्ग शामिल था। अपने शौर्य के लिए विख्यात यह वर्ग पुरानी परम्पराओं और मान्यताओं से चिपका हुआ है। इसका अहसास, प्रदर्शन के दौरान उपयोग की गयी अश्लील शब्दावली से हुआ। सभा के दौरान यह भी पता चला कि धर्मगुरु कहे जाने वाले शंकराचार्य के शिष्य ईश्वर की व्याख्या को लेकर उतने ही कट्टर हैं जितने भारत के अन्य अल्पसंख्यक। जाट-राजपूत का गठबंधन बनाने की चेष्टा में संलग्न लोकदल (ब) के नेता नाथूराम मिर्धा ने जब इस सभा को सम्बोधित करते हुए ईश्वर के निराकार स्वरूप की बात की, तो शंकराचार्य के शिष्य ब्रह्मचारी आशुतोष प्रकाश ने उत्तेजित होते हुए उन्हें 'मूर्ख' और 'अनर्गल प्रलापी' जैसे शब्दों से सम्बोधित किया। इस सभा में विपक्ष के नेता भैरोंसिह शेखावत अनुपस्थित थे। सती समर्थकों की इस सभा में उनके खिलाफ परचे बांटे गये। ये परचे जयपुर नगर राजपूत सभा के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह के नाम से जारी किये गये थे। इस परचे में श्री शेखावत के द्वारा २ अक्तूबर को दिवराला में दिये गये भाषण की निन्दा की गयी थी। परचे में कहा गया था, कि "मनुष्य कितना भी बड़ा हो, किसी भी पद पर पहुंच जाये, वह समाज से बड़ा नहीं हो सकता। बरनाला जो पंजाब के मुख्यमंत्री था, जब सिख ने उसे दोषी माना, तो उसने गुरुद्वारे के बाहर बैठ कर जूते तक साफ किये थे।" परचे का शीर्षक था 'गद्दारों से सावधान।'

सभा का माहौल हिन्दू और फिर राजपूत प्रमुखता सें अटा नजर आता था। प्रदर्शन में भाग लेने वाला हर राजपूत परम्परा के उस तेवर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कभी शासन करने का हक उसकी तलवार को हासिल था।

राज्य सरकार के पंगु बने प्रशासन के देखते-देखते 'धर्म रक्षा समिति' ने सभा में प्रस्ताव पारित किया कि दिवराला से गिरफ्तार किये निर्दोष लोगों को अगर दीपावली तक रिहा नहीं किया गया, तो दिवराला के साथ-साथ प्रदेश भर के हिन्दू घरों में रौशनी नहीं करेंगे। इसका अनुमोदन सारी सभा ने किया। इसके अतिरिक्त संघर्ष के लिए तैयार रहने और जन जागृति अभियान चलाने के प्रस्ताव पारित किये गये। कल्याण सिंह कालवी ने अपने भाषण में वही सब दोहराया जो वह पहले कहते रहे हैं।

निश्चित रूप से राजस्थान अब उसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जहां जान लेवा साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। प्रदेश में जाति के नाम पर बिहार जैसे झगड़े और चुनाव राजनीति में दाब-धौंस का सिलसिला बनेगा। अवसरवादी राजनेताओं व राजनैतिक दलों द्वारा सत्ता हथियाने अथवा बरकरार रखते के लिए सन १९५४ से राजस्थान में विभिन्न जातियों के ऐसे दस्ते तैयार करने शुरू किये थे, जो विधानसभा में उनके अल्पमत को बहुमत में बदल दे। १३ नवम्बर, १९५४ में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व० जयनारायण व्यास को शिकस्त देने के लिए जाट जाति के नेताओं को कांग्रेस संगठन ने जातिवाद का जामा पहना कर एकत्रित किया था। फिर सुखाड़िया सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के इशारे पर जाटों को सबक सिखाने के लिए लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जैसे सामंती तत्वों को कांग्रेस में शामिल कर राजपूतवाद को महिमामंडित किया गया था। इसके बाद की राजनीति राजस्थान में जातीय समीकरणों की राजनीति बन कर रह गयी। वर्तमान लोकदल (अ) के नेता कुम्भाराम चौधरी ने कांग्रेस विरोध के लिए झालावाड़ नरेश से मिलकर जाट-राजपूत का समीकरण बना कांग्रेस को अल्पमत में ला दिया था।

आज राजस्थान की राजनीति में हर राजनैतिक दल, चुनाव राजनीति के लिए जातीय गटक को अहम मान कर चलता है। नतीजा यह हुआ है कि परम्परा का घटिया स्वरूप और सामन्तवाद आज भी राजस्थान में निर्णायक बना हुआ है। राजस्थान के आम आदमी को इस अंधकूप में जीने के लिए यहां की यथास्थितिवादी कलमें और भाग्यवादी राजनेता बाध्य कर रहे हैं। **—ओम सैनी**

रही जो स्टेनगनों के जमाने में तलवारधारियों का प्रदर्शन देखने के लिए आ जुटे थे। तीस सितम्बर को सती प्रकरण में सरकार के रवैये के विरोध में राजपूत छात्र परिषद की ओर से ऐसा ही प्रदर्शन होना था। राजपूत छात्रावास के बाहर भारी संख्या में पुलिस और तमाशबीन भीड़ जमा थी। अचानक राजपूत युवकों ने फैसला किया कि वह तलवारों की जगह भगवा झण्डे लेकर निकलेंगे। 'माया' ने इस आयोजन के नेताओं से जब बदले रुख का कारण जानना चाहा तो उनका कहना था— "अभी माहौल इतना नहीं बिगड़ा कि तलवारें निकाली जायें। जब हालात हमारे खिलाफ होंगे तभी तलवारें निकलेंगी।" इसके बाद पांच सौ नवयुवकों ने भगवा झण्डों के साथ प्रदर्शन किया।

इन आयोजनों में सम्भवत: और तेजी आती, पर राज्य सरकार ने २९ सितम्बर से शुरू हुए विधानसभा सत्र को ३० सितम्बर की शाम ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए देर रात राज्यपाल से सत्रावसान की अधिसूचना भी जारी करवा दी। ऐसा इसलिए किया गया कि विजयादशमी के दिन सती-समर्थकों ने दिवराला में सती स्मारक बनाने की घोषणा की थी। वैसे अगर यह विधानसभा सत्र हो जाता, तो निश्चित रूप से विधानसभा का हां और ना पक्ष परम्परावादियों एवं सुधारवादियों में बंट जाता। कम-से-कम राजपूत बहुल विधानसभा क्षेत्रों का विधायक अपने दल की धारण के विपरीत सती-समर्थन में सर हिलाता नजर आता।

सरकार ने विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ घोषणा की थी दिवराला सती काण्ड पर सरकार छह अक्टूबर को बयान देगी। पर अचानक प्रधानमंत्री के निर्देश का बाद आलाकमान ने सारा संचालन अपने हाथ में ले लिया। विधानसभा का सत्र शुरू होने की सुबह मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाया गया। मुख्यमंत्री दिल्ली और जयपुर के बीच फिरकी की तरह घूमने लगे। फिर सत्रावसान करवाकर एक अक्तूबर को राजस्थान सती (निवारण) अध्यादेश १९८७ तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इस अध्यादेश की धाराओं के अनुसार सती होने के लिए उकसाने वाले को फांसी या उम्र कैद तथा सती होने का प्रयास करने वाली महिला को पांच साल की जेल व सती को महिमामंडित करने पर सात साल की कैद तथा सती स्थल ध्वस्त करने का कानून शामिल है।

आलाकमान ने प्रभारी महामंत्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ में दिये बयान को भी पसन्द नहीं किया। शायद यही वजह थी कि राज्य में अकाल पीड़ितों का जायजा लेने के लिए हेलीकाप्टर इस्तेमाल करने की परम्परा और मुख्यमंत्री के इस विशेषाधिकार को रद्द कर दिया गया है। फिर भी मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं—विशेष रूप से जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी व भाजपा विधायक एवं विपक्ष के नेता भैरोंसिह शेखावत के उपयोग को ध्यान में रखा। दिवराला में धारा १४४ लगने व सभाओं पर

पाबंदी के बावजूद दशहरे के दिन इन नेताओं को दिवराला में सभा करने की अनुमति दी गयी। पत्रकारों से इस नजारे को छिपाने के लिए उनके दिवराला पहुंचने पर रोक लगायी गयी। दिवराला में शेखावत ने सती प्रथा का विरोध तो किया, पर साथ ही इस प्रकरण से जुड़े 'बेगुनाह' लोगों की गिरफ्तारी पर अपनी नाराजगी प्रकट की। शेखावत ने लगे हाथ सती होने के बाद के अनुष्ठानों पर पाबंदी का विरोध भी सभा में दर्ज करवा दिया। इस तरह एक ओर शेखावत ने मुख्यमंत्री जोशी को राजपूतों का कोपभाजन होने से बचाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर कल्याण सिंह कालवी के आन्दोलन में अपने को शामिल कर लिया।

वैसे विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखाक्त खुद धर्मसंकट में फंस गये हैं। अब तक राजस्थान में सामान्य राजपूतों का उन्हें एक छत्र नेता माना जाता था, पर दिवराला में उनकी लम्बी अनुपस्थिति और कल्याण सिंह कालवी की पहल ने उन्हें दो नम्बर का नेता बना दिया। कल्याण सिंह

वैसे विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत खुद धर्मसंकट में फंस गये हैं। अब तक राजस्थान में सामान्य राजपूतों का उन्हें एक छत्र नेता माना जाता था, पर दिवराला में उनकी लम्बी अनुपस्थिति और कल्याण सिंह कालवी की पहल ने उन्हें दो नम्बर का नेता बना दिया। कल्याण सिंह

कालवी जहां जनता पार्टी के अध्यक्ष से मात्र राजपूत नेता बनने के भंवर में फंस चुके हैं, वहीं शेखावत राजपूत नेता के बजाय केवल भाजपा नेता नजर आ रहे हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए दोनों नेताओं ने प्रयास किये हैं। इस प्रयास के तहत आठ अक्तूबर को जयपुर में 'धर्म रक्षा समिति' की ओर से आयोजित रैली में प्रान्तीय भाजपा, जनता और लोकदल के नेताओं को एक मंच पर एकत्रित करने का कार्यक्रम था। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक राज्य सरकार ने आठ अक्तूबर को जयपुर में जुलूस निकालने, हथियार लेकर चलने और सभा करने पर पाबंदी लगा दी थी। बहरहाल दोनों नेता कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राजपूत समुदाय भी नाराज न हो और वे एक धर्मनिरपेक्ष नेता भी बने रहें। दरअसल जयपुर में गठित 'धर्म रक्षा समिति' और दिवराला की 'सती समारोह समिति' ने सारा मामला राजपूत समुदाय का मामला बनाने की कोशिश की है। बाद में इस समुदाय ने अपनी अल्प संख्या पर गौर किया और किस्से को हिन्दू धर्म के साथ जोड़ दिया, ताकि वे जातिवाद के आरोप से मुक्त हो सकें। सती-समर्थकों ने विभिन्न धर्म प्रमुखों से भी सम्पर्क स्थापित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ ने सती प्रथा का समर्थन कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा है— "राजा राममोहन राय द्वारा तथ्यहीन आधारों पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने से ही देश में विधवाओं की समस्या पैदा हुई है।" शंकराचार्य ने सती प्रथा के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा है कि सती धर्म के औचित्य और शास्त्रीयता के बारे में कोई भी गोवर्धनपीठ पुरी आकर उनसे वाद-विवाद कर सकता है। धर्मशास्त्रों की मदद लेने वाले नेताओं ने प्रारम्भ में घोषणा की थी कि सती प्रथा के खिलाफ हैं, पर पुरी के शंकराचार्य के इस बयान की किसी ने भी आलोचना नहीं की। मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों को चलाने की इजाजत चाहने वालों का वास्तविक चेहरा तब औ स्पष्ट हो गया, जब उन्होंने जयपुर में धर्म रक्षा समिति की आठ अक्तूबर की उस सभा में भाग लेने का निर्णय कर लिया, जिसमें सती समर्थक धर्म गुरू हिस्सा ले रहे थे। धर्म रक्षा समिति ने अपने आन्दोलन में राजपूत होने के कारण 'जनमोर्चा' के नेता एवं पूर्व रक्षामंत्री वी॰पी॰ सिंह को जोड़ने का प्रयास भी किया है। पर वी॰पी॰ सिंह ने उनके निमंत्रण को ठुकराते हुए मथुरा में संवाददाताओं से बात करते हुए दिवराला सती काण्ड को निहायत शर्मनाक और बर्बर बताया। अब धर्म रक्षा समिति के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में विभिन्न धर्म भीरु हिन्दुओं को जोड़कर सती प्रथा जैसे कुकृत्य को महिमामंडित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसे सरकार दबा पाने में अब तक असमर्थ रही है।

छाया : गोपाल संगर

মহিলাদের একমাত্র সম্পূর্ণ পত্রিকা
মনোরমা
ন্যাগিং
আপনি কি এই ঘ্যানঘ্যান-এ মনোরোগের শিকার?

अब बंगला 'मनोरमा' बंगला पाठकों के लिए अब मित्र प्रकाशन की नयी भेंट- 'मनोरमा'

बंगला 'मनोरमा' की प्रति आज ही सुरक्षित करायें

When you are searching Your interest areas in an English magazine....
....Take a look at PROBE
INDIA

PROBE
An Appeal to You
ANTULAY Splitting the Cong
REKHA "I still need romance"
Abbas & Uma Vasudev
Reddy Report on Sexuality in Madras
Battle of the Blouse

If business, investment climate and the share market are the areas of your interest, Probe has some of the most investigated reports on the contemporary scene to share with you.

If it is the political scene, you will be more than satisfied with the objective reports from all around the country.

There is almost everything in Probe, you could look for-sports, cinema, media, focus on international scene, women, lifestyle, human interest and regional coverages.

And for your leisure you have the visual delight of photo-features.

Probe is an interesting and bold blend of topical coverage with an insight into the future, for we take a stand on controversial issues.

PROBE
INDIA
Reporting with credibility that's seeded within.

सती प्रकरण

विरोध, मगर अन्तर्विरोध

विरोध या समर्थन : सभा में उपेक्षित मंत्री श्रीमती कमला, शीला दीक्षित, प्रतिभा पाटिल, बीना काक, जकिया इनाम

धर्मओर जाति केनाम पर
याचारो की हम निन्दा

विरोध का एक अनुकरणीय स्वर : एक सभा में बोलते हुए ग्रामीण महिला नौरती देवी

जिस तरह महिला एवं सामाजिक संगठनों की ओर से दिवराला के सती कांड के खिलाफ बयान जारी किये जा रहे थे, उससे लगता था कि इन संगठनों द्वारा ६ अक्टूबर को जयपुर में आयोजित रैली में लगभग दस हजार लोग हिस्सा लेंगे। पर सरकारी अनुदानों पर टिके और भव्य भवनों में दफ्तर चलाने वाले इन संगठनों को अपनी बात कहने और सुनाने के लिए सरकारी भीड़ पर आश्रित होना पड़ा। कांग्रेस दल के विधायकों और संगठन के स्थानीय नेताओं ने बच्चों और महिलाओं की तीन हजार के लगभग भीड़ जुटायी, जिसका नेतृत्व करने के लिए तुरन्त वे बुद्धिजीवी महिलाएं आगे आ गयीं, जिनका आम महिलाओं की जिन्दगी से कोई ताल्लुक नहीं है। हां, यह जरूर हुआ कि इस भीड़ में ब्यावर की श्रीमती नौरती देवी जैसी देहाती महिला का बेलाग भाषण जरूर हुआ। आयोजकों ने आम महिला की पहचान के रूप में श्रीमती नौरती देवी को मंच पर खड़ा किया, उनका भाषण सुना और आश्वस्त हो गये कि ग्रामीण सती-प्रथा की बुराई के खिलाफ सजग हैं।

मौन जुलूस में मुखर युवतियां, महिला-नेता सती प्रथा के खिलाफ बैनर थामे थीं। पुलिस संरक्षण में यह जुलूस दिन के एक बजे जयपुर के राम निवास बाग के अलबर्ट हाल के पास से रवाना हुआ। बैनरों पर लिखा था। सवाल है नारी की पहचान का, सवाल है नारी के सम्मान का, बहन जले, बेटी जले सती प्रथा क्यों चले। इस जुलूस में जयपुर के महिला संगठनों के अतिरिक्त दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर और पूना के कई संगठन शामिल थे। आयोजकों के अनुसार कुल संगठनों की संख्या २५ थी।

शहर में तीन किलोमीटर का चक्कर लगाने के बाद रामलीला मैदान में सभा का आयोजन किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व घोषणा के अनुसार जुलूस में न सही, पर आम सभा में दिल्ली से आयीं केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, संसदीय कार्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित और राज्यसभा की उपसभापति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जरूर हिस्सा लेंगी।

बाद में पता चला कि स्थानीय महिला संगठनों ने पांच तारीख की रात ही फैसला कर लिया था कि केन्द्र और राज्य सरकार की महिला मंत्रियों और विधायकों को न तो सभा में मंच पर आने दिया जायेगा और न ही जुलूस में आगे बैनरों के साथ चलने दिया जायेगा। इस निर्णय की वजह यह बतायी गयी कि विधायक एवं महिला मंत्रियों ने सती प्रकरण में कभी सरकार से परे जाकर जुबान नहीं खोलीं और न ही दिवराला गयीं। बहरहाल महिला मंत्री जुलूस में तो नहीं, पर जब सभा स्थल पर पहुंचीं, तो नजारा दूसरा था। सभा स्थल पर पहुंचने वाली महिला मंत्रियों में प्रदेश की राजस्व मंत्री श्रीमती कमला पहली मंत्री थीं। वह बीमारी की हालत से उठकर आयी थीं, उन्हें ज्ञात नहीं था कि महिला संगठनों ने क्या निर्णय ले रखा था। वह सीधे मंच पर जाकर बैठ गयीं, तभी प्रदर्शन की संयोजिका कुमारी हेमलता प्रभू ने एक चिट लिखकर भेजा, जिसमें राजनेताओं को श्रोताओं में बैठने का निर्णय दर्ज था। श्रीमती कमला आश्चर्य के साथ उठीं और पत्रकारों के पास आकर बैठ गयीं। फिर श्रीमती शीला दीक्षित, उपमंत्री बीना काक और स्वास्थ्य मंत्री जकिया इनाम के साथ श्रीमती प्रतिभा पाटिल आयीं, वह भी श्रीमती कमला के पास बैठ गयीं। इस बीच गायन और भाषण चलते रहे। जब श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने पंडाल में प्रवेश किया, तो आयोजकों ने 'हम होंगे कामयाब एक दिन' के सामूहिक गान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा कर दी।

सभा के बाद जब उपस्थित मंत्रियों से उनके साथ हुए व्यवहार के सम्बन्ध में जानना चाहा, तो उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। इसी दिन शाम श्रीमती वाजपेयी ने अपने साथ की केन्द्रीय महिला मंत्रियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में हुई उपेक्षा के संदर्भ में कहा कि वह और उनकी साथी राजस्थान में हुए सती कांड पर महिलाओं की ओर से किये जा रहे विरोध को समर्थन देने आयी थीं। पर आयोजकों को कोई गलतफहमी हो गयी। उन्होंने कहा कि यह कहना ठीक नहीं कि सती प्रकरण में राज्य की महिला मंत्रियों और महिला विधायकों का मानस सती कांड का विरोध करने का नहीं था।

राजस्थान राजपूत महिला संघ की अध्यक्ष श्रीमती बीनू जोधा भी इस सम्मेलन में उपस्थित थीं। माया ने उनसे दिवराला सती कांड पर टिप्पणी चाही, तो उनका कहना था—"इस सम्मेलन में यह गलत कहा जा रहा है कि रूपकंवर को जबरन जलाया गया। वैसे भी सती प्रथा के विरुद्ध हूं। इसीलिए बगैर किसी निमंत्रण के आयी हूं।" उन्होंने सम्मेलन के आयोजकों की ओर इशारा करके कहा कि इनसे कहो गांवों की ओर मुंह करें। शहर में तो कोई सती होती नहीं है और जहां सती होती हैं, वहां जाने में इनके पैरों में छाले पड़ते हैं। श्रीमती जोधा कह रही थीं कि जब तक समाज औरत को हर हाल में सम्मान के साथ जीने के साधन मुहैया नहीं करायेगा, तब तक कुप्रथाएं समाप्त नहीं होंगी।

—ओम सैनी

क्या लोकदल-ब कांग्रेस-इ का विकल्प होगा ?

अभी चुनाव काफी दूर हैं और विपक्षी राजनीति नित्य नये रूप धारण करती जा रही है, इसलिए यह बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि कोई विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल का विकल्प है। लेकिन, राजस्थान में पिछले दिनों लोकदल-ब की जो शक्ति और रणनीति दिखायी पड़ी है, उससे ऐसा लगता है कि यह दल प्रदेश में तेजी से उभर रहा है। लोकदल-ब बाकी दलों से भारी क्यों पड़ रहा है ?

प्रभावशाली प्रदर्शन : देवी लाल का जनसभा में भाषण

राजस्थान के पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में लोकदल की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश की विपक्षी राजनीति में हेमवती नन्दन बहुगुणा का लोकदल में वर्चस्व बढ़ने लगा है। फरवरी माह में विभाजन की मार का शिकार लोकदल दो हिस्सों में बंटकर बेअसर लगने लगा था। बहुगुणा की अध्यक्षतावाले लोकदल की बागडोर प्रदेश में नाथूराम मिर्धा के हाथ में है, जबकि अजीत सिंह वाले गुट का नेतृत्व किसान यूनियन के नेता दौलतराम सारण और चौधरी कुम्भाराम आर्य थामे हैं। लोकदल के युवाओं का रुझान प्रदेश में अजीत सिंह गुट के साथ होने से अंदाज लगाया जा रहा था कि अन्ततः दौलतराम सारण बाजी मार ले जायेंगे, पर हो इसके विपरीत रहा है।

किसान यूनियन जैसे प्रभावी संगठन और युवाओं के सहयोग के बावजूद हरियाणा की हवा ने अजीत सिंह गुट को प्रदेश की किसान राजनीति से काट कर रख दिया है। इस बीच सुस्त समझे जाने वाले लोकदल के विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा ने ३० अगस्त को जयपुर में किसानों की ऐसी रैली का आयोजन किया. जिसने न केवल अजीत सिंह गुट को पस्त कर दिया, बल्कि प्रदेश जनता पार्टी को चन्द्रशेखर की पकड़ से आजाद कर लोकदल-ब में आ मिलने के लिए लालायित किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज समझे जाने वाले विपक्ष के नेता भैरो सिंह शेखावत को अपनी सौदेबाजी की ताकत समाप्त होती नजर आने लगी है।

विशाल रैली : तीस अगस्त को आयोजित यह रैली लोकदल-ब ने अपने प्रादेशिक सम्मेलन के सिलसिले में की थी। ढाई लाख लोगों को समा लेने की क्षमता रखने वाले जयपुर के राम निवास बाग में एक लाख किसानों का जमघट, इस अवसर पर आमंत्रित हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल, लोकदल अध्यक्ष हेमवती नन्दन बहुगुणा और कर्पूरी ठाकुर को देखने के लिए चिलचिलाती धूप में जमा था। आश्चर्यजनक रूप से इस सम्मेलन में उत्तेजना, उत्साह की जगह लोगों के चेहरों पर अकाल की खामोशी छायी हुई थी। स्थायी परिवर्तन की सूचक यह खामोशी एक ऐसी दृढ़ता का परिचय दे रही थी जो वक्त के साथ गुम नहीं होती।

लोकदल-ब का यह आयोजन उस स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो गया जब कांग्रेस-इ अपनी सिर फुटव्वल से प्रदेश और केन्द्र में अपना वर्चस्व खो रही है। प्रदेश की हरिदेव जोशी सरकार को गिराने के लिए उन्हीं के दल के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया सक्रिय हैं। यह अलग बात है कि कांग्रेस-इ आलाकमान मुख्यमंत्री को बनाये रखने के लिए अपने अनुशासन के अंकुश से असंतुष्टों का सिर दबोचे हैं, पर अकाल और सूखे से पीड़ित किसान कांग्रेस से कट रहा है। परिवर्तन की चाह लिये किसानों को लोकदल-ब ने अपने में समेटा है, जबकि प्रदेश भाजपा और जनता पार्टी का नेतृत्व लोगों से कुछ कह पाने में असमर्थ है। उधर माकपा और भाकपा का नेतृत्व ट्रेड यूनियनों तक सिमट कर रह गया है। इनके नेता अपने-अपने विधान सभा-क्षेत्रों को कब्जे में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विहीन सरकार से किसानों अथवा आम लोगों को किसी प्रकार की राहत दिला पाने में अक्षम हैं।

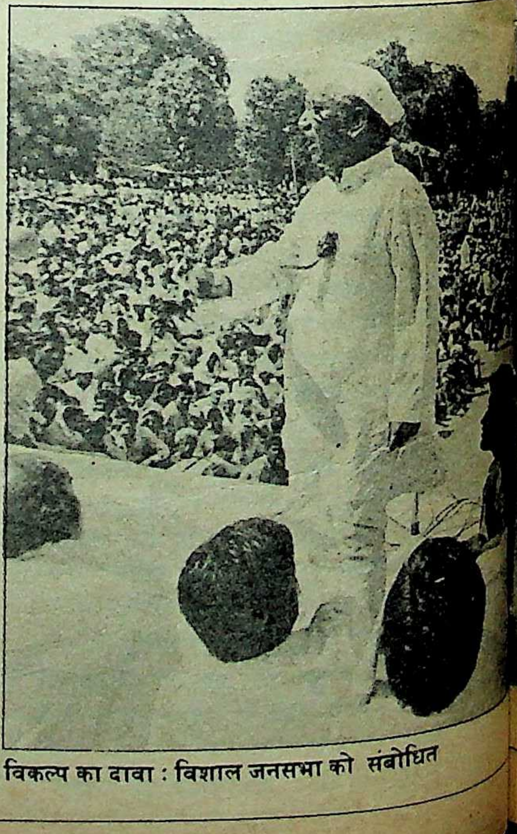
विकल्प का दावा : विशाल जनसभा को संबोधित

ऐसे माहौल से लोगों की धारणा सरकार बदलने की होने लगी है, पर नेतृत्व के अभाव में उत्तेजना और उत्साह की जगह जड़ता ने ले रखी है। इस जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया है, लोकदल-ब ने। अपने प्रादेशिक अधिवेशन के दौरान लोकदल-ब ने अपने राजनैतिक प्रस्ताव में वर्तमान केन्द्र की कांग्रेस-इ सरकार को समाजवाद से नाता तोड़ने वाली बताते हुए मांग की है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने पद से त्याग-पत्र देकर लोकसभा के मध्यावधि चुनाव करायें। साथ ही राजस्थान के अन्य विपक्षी दलों से अनुरोध किया है, "कांग्रेस-इ के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने हेतु प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए बुनियादी नीतियों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण करके लोकदल के जन-आंदोलन को समर्थन व सहयोग प्रदान करें।"

समर्थन और सहयोग की मांग प्रदेश के विपक्षी दलों की ऐसी शतरंजी चाल है, जिसके तहत एक दल मांग करता है, तो दूसरा उसमें अपने अस्तित्व का संकट देखता है। मसलन, जब तक प्रदेश में आम लोगों की गोलबंदी नहीं हुई थी तब तक हर दल अन्य दलों से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा कर रहा था पर जैसे ही लोकदल-ब का एक लाख लोगों का सम्मेलन जयपुर में संपन्न हुआ, वैसे ही अखिल भारतीय नेताओं के लिए सहयोग और समर्थन विचार का प्रश्न मान लिया गया।

विलय का उलझता सवाल : लोकदल-ब के साथ विलय के सवाल पर जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी का विचार था, "हम चाहते हैं, सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक हो जायें। दो पार्टियों का सिस्टम (पद्धति) हिंदुस्तान में विकसित हो, मैं हमेशा इसके पक्ष में रहा हूं। अलग-अलग रहेंगे तो हम कांग्रेस-इ को नहीं हटा

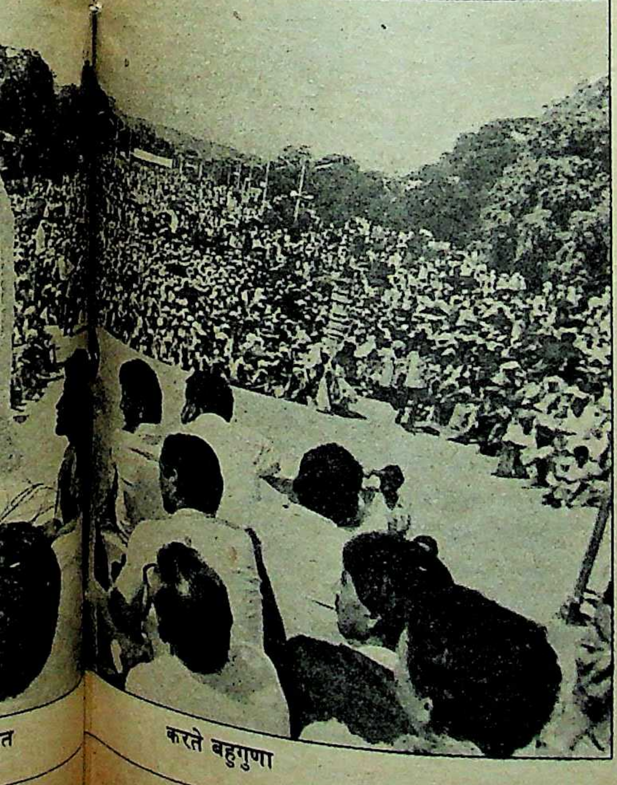

त

करते बहुगुणा

साक्षात्कार/दौलत राम सारण

'जनमत के प्रबल दबाव से ही विपक्षी एकता'

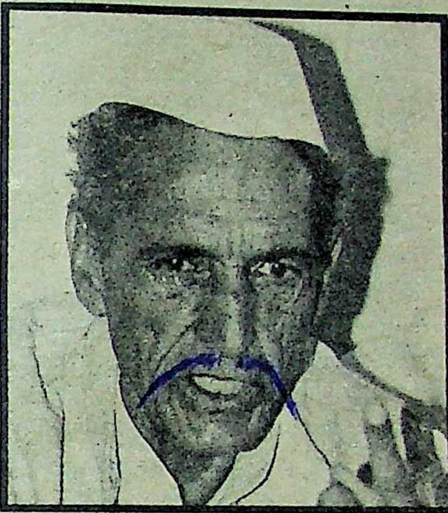

बहुगुणा समर्थित लोकदल के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा भले ही लोकदल-अ के अध्यक्ष दौलतराम सारण को कमजोर साबित करते हों, पर यह वास्तविकता है कि राजस्थान की राजनीति में श्री सारण ईमानदारी के पर्याय बने हुए हैं। किसानों को संगठित करने में लोकदल-ब के पहले उनका कोई मुकाबला नहीं था। मात्र कम्युनिस्ट पार्टियों के किसान संगठन ही राजस्थान की राजनीति में असरदार हुआ करते थे, पर जैसे-जैसे उनकी पकड़ कमजोर हुई श्री सारण ने किसान यूनियन के माध्यम से किसानों के प्रभावी आंदोलन आयोजित किये हैं। लोकदल के विभाजन और राजस्थान में कमजोर विपक्ष के लिए वह कितने जिम्मेवार हैं, इस सम्बन्ध में 'माया' ने उनसे खुली बातचीत की। प्रस्तुत हैं, साक्षात्कार के प्रमुख अंश :

माया : प्रदेश में लोकदल के विभाजन के बाद से विपक्ष बिखरता हुआ नजर आता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

सारण : जो लोग कांग्रेस-इ हटाने की बात करते हैं, वे ही मुख्यमंत्री को रखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं। इसी तरह जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देकर कांग्रेस-इ को मजबूत बनाते हैं वे ही फिर हमारी पार्टी के लिए कहते हैं कि यह कोई पार्टी ही नहीं है। विपक्ष के ऐसे लोग जिम्मेवार हैं, विपक्ष को कमजोर करने के लिए।

माया : निकट भविष्य में आपका विभाजन समाप्त होने की कोई सम्भावना ?

सारण : जिन लोगों ने लोकदल को तोड़ा है, उनको सद्बुद्धि आ जाये, तो कभी भी एकता हो सकती है।

माया : यानी आप नाथूराम मिर्धा को इस टूट के लिए जिम्मेवार मानते हैं ?

सारण : मिर्धा ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव, देवीलाल, बहुगुणा ये सभी लोग जिम्मेवार हैं, लोकदल के विभाजन के लिए।

माया : इसमें कहां तक सच्चाई है कि विपक्ष की एकता में कालवी, शेखावत, मिर्धा और मुख्यमंत्री श्री जोशी की अन्तरंगता बाधक बनी हुई है ?

सारण : यह मुझसे अधिक राजस्थान का प्रेस जानता है और राजस्थान की जनता जानती है।

माया : विपक्ष की एकता के सम्बन्ध में लोकदल-अ का सोच क्या है ?

सारण : विपक्ष की एकता कुछ नेताओं के जोड़-तोड़ से सम्भव नहीं होगी। विपक्ष की एकता जनमत के प्रबल दबाव के आधार पर ही सम्भव है। हमारा विश्वास यह है कि एक निश्चित कार्यक्रम के तहत एकता के प्रयास होने चाहिए तभी सही एकता सम्भव होगी।

माया : सूखे और अकाल से पीड़ित जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

सारण : पिछले एक माह (अगस्त) से हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। जन-जागरण के साथ-साथ पीड़ित लोगों को गोलबन्द कर रहे हैं।

माया : क्या लोकदल का विभाजन किसानों की गोलबन्दी में बाधक नहीं बनेगा ?

सारण : पीड़ित लोगों में 'अ' और 'ब' का विभाजन नहीं है। फिर भी कोई अगर विभाजन की कोशिश करेगा, तो उसे जागरूक किसान समझता है।

माया : जनता पार्टी का लोकदल-ब में विलय होने पर आपके सामने भी एकता का सवाल आये, तो आप क्या करेंगे ?

सारण : यह काल्पनिक सवाल है। हमारा बहुत साफ दृष्टिकोण है, हम जनहित के लिए विपक्ष में काम करना चाहते हैं।

माया : हरियाणा में लोकदल-अ को जनता ने नकारा है, आप क्या मानते हैं ?

सारण : हरियाणा में लोकदल-अ खड़ा ही नहीं हुआ था। लोकदल के विभाजन के बाद जब एकता की बात चल रही थी, तभी चौधरी चरणसिंह का देहान्त हो गया था। ग्यारह दिन तक लोग उसमें लगे रहे। लोकदल-अ के लोग चुनाव के पांच दिन पूर्व हरियाणा में गये थे। तब तक यह माहौल बन गया था कि लोकदल-अ चुनाव ही नहीं लड़ रहा। मतदाता ने लोकदल के विभाजन को महसूस ही नहीं किया।

माया : श्रीमती चरण सिंह की हार को क्या कहेंगे ?

सारण : श्रीमती चरण सिंह की हार का भी यही मोटा कारण था।

माया : आप हरियाणा के चुनावों को शक्ति परीक्षण नहीं मानते ?

सारण : बिलकुल नहीं।

—ओम सैनी

साक्षात्कार /नाथूराम मिर्धा

'सबके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे'

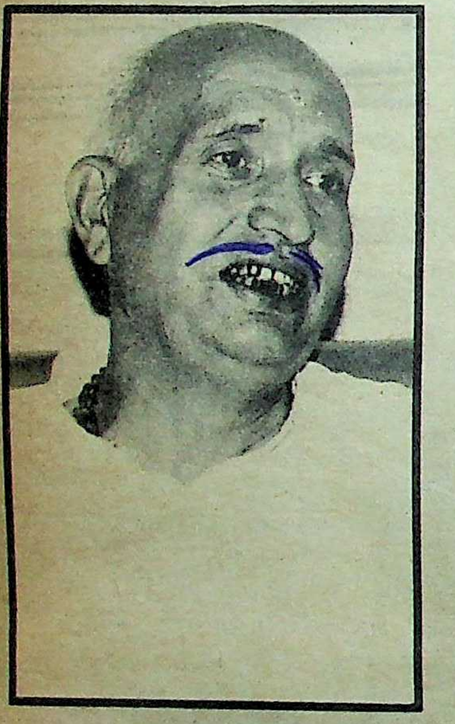

परिवर्तित राजनीतिक माहौल में प्रदेश के लोकदल-ब ने अपने जन आधार का अहसास ३० अगस्त को राजधानी जयपुर में आयोजित सम्मेलन से कराया है। बावजूद इसके बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके समाधान के बगैर लोकदल-ब किसान ताकत को अपने साथ स्थायी रूप से नहीं जोड़ पायेगा। मसलन लोकदल-अ के नेता अगर बहुगुणा समर्थित लोकदल का विरोध जारी रखते हैं तो उसका कांग्रेस-इ का विकल्प बनने का यथार्थ स्वप्न में बदल जायेगा। इसी सन्दर्भ में लोकदल-ब के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा से माया ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं, बातचीत के मुख्य अंश :

माया : आपके प्रादेशिक सम्मेलन के दौरान आयोजित रैली से क्या आप यह समझते हैं कि राजस्थान से अजीतसिंह समर्थित लोकदल का प्रभाव समाप्त हो गया ?

मिर्धा : अजीत सिंह समर्थित लोकदल राजस्थान में तीन-चार आदमियों के अलावा कुछ भी नहीं हैं। इनमें से दो तो विधायक यदुनाथसिंह और नवरंगसिंह फिर माहिर आजाद और दौलतराम जी...और एक वो सीकर वाला...भाई क्या नाम है उसका, हां गोपालसिंह, इन आदमियों के सिवाय (अलावा) न तो इनके पास कार्यकर्ता हैं और न ही इनका असर है लोकदल पर। इनका असर तो हरियाणा के चुनाव के बाद ही खतम हो गया। हरियाणा के चुनाव के बाद इनकी गतिविधियां इतनी कमजोर हो गयी हैं कि ये लोग जहां कहीं कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, बिखर जाते हैं। हमारी रैली हो रही थी, तब यह प्रचार था कि इसमें किसी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कहते रहे कि भाई आप नाथूरामजी के साथ क्यों लगे हो, वो तो गोरमेन्ट (सरकार) से मिले हुए हैं। इस तरह के प्रचार को लोग सब समझते हैं कि यह झूठ से भरा हुआ है। उनकी बात तो लोग पहले भी नहीं मानते थे। और इस रैली के बाद तो वो कम्पलीटली (पूरी तरह से) एक्सपोज (उजागर) हो गये। अब जब कभी वह (लोकदल-अ) कोई जलसा करें तो पता चले कि इनका असर कैसा है।

माया : चौधरी कुम्भाराम के असर के बारे में आपका क्या खयाल है ?

मिर्धा : चौधरी कुम्भाराम जी तो जब पहले एकता के प्रयास में विफल हो गये. तो करीब-करीब अलग से हो गये। आजकल अपने फार्म पर आराम करते हैं और जो छोटा-मोटा उद्योग उनका है, उसकी देखभाल करते हैं। वह राजनीति में कतई सक्रिय नहीं हैं।

माया : क्या आप नहीं समझते कि किसान यूनियन संगठन के माध्यम से लोकदल-अ के अध्यक्ष दौलतराम सारण आज भी प्रदेश के किसानों में असर रखते हैं ?

मिर्धा : किसान यूनियन का संगठन सब पार्टियों के किसान संगठनों के इकत्रित होने का कभी मंच था। अब सब पार्टी के लोग भी इनकी सारी पोल को समझ गये। दौलतराम जी की ओर से कोई एडीसन इस संगठन में नहीं होता तो बाकी संगठनों ने भी इसमें शामिल होना बन्द कर दिया होता। यूनियन के नाम पर किसान को यह इकत्रित कर लेते थे, वो क्राइसिस (परेशानी) भी अब करीब-करीब समाप्त हो गया। आज इस संगठन के सारे वर्कर लोकदल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं।

माया : भविष्य में चौधरी कुम्भाराम और दौलतराम सारण से समझौता करेंगे या नहीं ?

मिर्धा : समझौता करने की जरूरत नहीं है, जब इनकी और हमारी नीतियां ही एक दूसरे से मेल नहीं खातीं। जिस अजीतसिंह को यह नेता मान कर चलते हैं उस अजीत सिंह की न तो किसानों को लेकर कोई सेवाएं हैं और न कभी उन्होंने राजनीति में रह कर कोई काम किया है। मैंने स्वयं अजीतसिंह को लोकदल में जब भर्ती किया था, तो सोचा था कि भाई यह सबके साथ मिल कर काम करेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। पर भाई दौलतराम और कुम्भाराम ने राजस्थान में और चन्द्रावती व कुछ उसके साथियों ने हरियाणा में, ऐसे ही यू०पी० के कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया—'अजीतसिंह ! तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।' इस तरह का गलत नारा देकर इन लोगों ने लोकदल का विभाजन अपने निजी स्वार्थों के लिए करवाया। फिर जिस पार्टी का आधार ही असत्य और अन्याय पर टिका हो, उसके साथ समझौता करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।

माया : जनता पार्टी से विलय की उम्मीद आप किस आधार पर कर रहे हैं जबकि आपका केन्द्रीय नेतृत्व चन्द्रशेखर की शर्तें मानने को तैयार ही नहीं है।

मिर्धा : जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में भी दो तरह के विचार चलते हैं। कुछ लोग एक होने की बात कहते हैं और कुछ लोग दूसरी राय रखते हैं। इसी तरह से हमारे प्रांत की जनता त्र पार्टी के लोग अपनी तरह से सोचते हैं। उनमें ज्यादातर जनता पार्टी के लोकदल-ब में मिलने के हामी हैं। अब देखना यह है कि अपना निर्णय वे क्या करते हैं।

माया : किसानों में जाट-राजपूत वाला भेद क्या आज असरदार नहीं है ?

मिर्धा : जाट-राजपूत का विवाद तो आज राजस्थान में काफी हद तक समाप्त हो गया है। हम दोनों के आपसी समझौते (यानी जनता पार्टी अध्यक्ष ठाकुर कल्याणसिंह कालवी) से सारी स्थितियां बदल गयीं और विलय होने के बाद तो बिलकुल ही समाप्त हो जायेगा। सब लोग एक होकर चलेंगे।

माया : जनता पार्टी में शामिल जागीरदारों से आपकी कैसे निभेगी ?

मिर्धा : अब जागीरदार तो कोई रहा नहीं, सब पर सिलिंग लागू हो गयी। इसलिए अब तो सब किसान हैं।

माया : रैली से बने माहौल को आप किस तरह बरकरार रखेंगे ?

मिर्धा : राजस्थान में लोकदल का प्रादेशिक सम्मेलन ही बहुत अरसे बाद हुआ है। फिर राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। २७ जिलों तक पहुंचने में समय लगता है। हम लोगों में जन-जागरण के लिए जिला सम्मेलन करेंगे। विधान सभा क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लेवल से संगठन बनायेंगे और दूसरी तरफ जिला सम्मेलनों में लोगों से पैसा इकत्रित कर जिला संगठनों को देंगे, ताकि संगठन ठीक से काम कर सके।

माया : आम आदमी की परेशानी का समाधान आपकी मुहिम में शामिल है या नहीं ?

मिर्धा : बिलकुल है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबों के कर्जे हम माफ करवायेंगे। बेरोजगारों

के लिए रोजगार देने के लिए उद्योग धंधे बढ़ायेंगे। सभी वृद्धों को पेंशन देने के लिए फिर सरकार से लड़ेंगे। फिलहाल अकाल की मार से लोगों को बचायेंगे। सरकार पर निगाह रखेंगे। पर हर समस्या के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते। आंदोलन का मतलब बात मनवाना होता है और जब लगेगा, बात नहीं मानी जा रही तो सबके साथ मिल कर आंदोलन करेंगे।

माया : आप समझते हैं कि अपनी मुलायमियत और सत्ताधारी दल के नेता से संबंधों के बावजूद आप अपना जन आधार बरकरार रख सकेंगे ?

मिर्धा : मेरा जन आधार आप खुद जानते हैं। पैंतालीस साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। मेरा जन आधार न तो इनके (मुख्यमंत्री) संबंधों से बिगड़ता है, न बनता है। जन आधार मेरी सेवाओं की वजह से बना है। आज भी राजस्थान में कोई घर ऐसा नहीं है, जो मेरे नाम अथवा सेवा से परिचित न हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, जिसका मैंने कोई न कोई काम न किया हो। मेरे आचरण और चरित्र को राजस्थान का किसान बहुत अच्छी तरह से जानता है।

माया : प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या किसान ताकत के रूप में लोकदल को उभरने देगा ?

मिर्धा : हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई मेरी समझ से टकराव नहीं है। वह अपने क्षेत्र में काम करते हैं और कहीं-कहीं कामन क्षेत्रों में हम सब साथ काम करते हैं। कभी हम मिलजुल कर जलसे बुलाते हैं कभी अलग-अलग जलसे करते हैं, इसमें टकराव कहां होगा ? न हम उनकी कोई बुराई करते हैं और न वो हमारी कभी बुराई करते हैं। विपक्ष एक हो, कांग्रेस-इ से सत्ता छीनी जाये, इस प्रयास में वह भी लगे हुए हैं और हम भी।

माया : क्या दोनों दलों के आर्थिक दृष्टिकोणों में कोई अन्तर नहीं ?

मिर्धा : हां इसे लेकर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हम लोग थोड़ा ग्रामीण ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, वो थोड़ा व्यापारियों वगैरह के लिए भी सोचते हैं।

माया : इस सोचने से कोई टकराव नहीं होगा ?

मिर्धा : नहीं, नहीं होगा।

माया : जनता पार्टी के आपके दल में विलय के बाद कुछ निर्दलीय सदस्यों के मिल जाने पर आपका दल विधान सभा में दूसरे नम्बर का हो सकता है। ऐसे में क्या विपक्ष के नेता पद को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है ?

मिर्धा : पहली बात तो निर्दलीय अपनी आजादी क्यों खोयेंगे, दूसरे अभी जनता पार्टी का विलय हुआ नहीं है और तीसरी बात यह क्या जरूरी है कि विपक्ष का नेता बदला ही जाये ?

—ओम सैनी

सकेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऐसा ही चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह पूछे जाने पर कि उसे लेकर आपके मन में कोई शंका तो नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि यह आल इंडिया नेतृत्व के विचार का विषय है, हम इसमें क्या कह सकते हैं ? वैसे जनता पार्टी ने अपने पांच नेताओं की कमेटी कार्यक्रम बनाने के लिए गठित की है, जिसके सदस्य बीजू पटनायक जार्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े और इंदूभाई पटेल हैं।

ऐसा बताया जाता है कि कल्याण सिंह कालवी को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का विशेष विश्वास हासिल है, लेकिन कालवी का कहना था, "हम राजीव के प्रति जितने आक्रामक हैं, उतने ही इनके (हरिदेव जोशी) प्रति भी। अब केवल बात बनाकर लोगों को प्रोवोक (उकसाने) करने से कोई मतलब नहीं है। ऐक्शन (कार्यक्रम) जो हमारा है, वह तो चल ही रहा है।"

रा०ज०पा० अध्यक्ष : कालवी

भाजपा नेता शेखावत

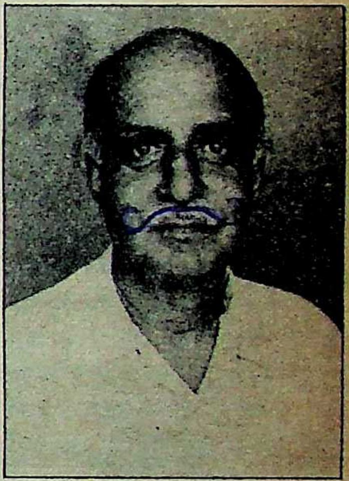

स्व० राजा मानसिंह

कल्याण सिंह कालवी जनता पार्टी के राजस्थान में सर्वमान्य नेता हों और जनता पार्टी के सारे सदस्यों की उनमें आस्था हो, ऐसी भी बात नहीं। माणक चंद सुराणा पार्टी में ही उनके प्रतिद्वंद्वी नेता हो गये हैं। लोकदल-ब से विलय के सवाल पर उनका विचार है, "यह पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, कालवी कैसे कर सकते हैं ? और अगर कालवी करेंगे, तो अपनी हद तक कर सकते हैं।" यों इस जवाब के पीछे जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी भी नजर आती है। दरअसल, लोकदल-ब के विधायक मोहन प्रकाश और जनता पार्टी के पूर्व विधायक गोपाल पचेरवाल तथा प्रदेश की ओर से युवा जनता की राष्ट्रभाषा कार्यसमिति के सदस्य श्रीचंद्र मेहता, जार्ज फर्नांडीस द्वारा गठित हिंद्र मजदूर किसान पंचायत की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष अर्जुन देथा व गंगानगर जिले की जनता पार्टी के अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ऐसे लोग हैं, जो दोनों दलों में विद्यमान समाजवादी गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पांचों युवा नेता जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री मास्टर रामशरण अन्त्यानुप्रासी के अनुयायी हैं। अलग-अलग दलों में होने के बावजूद नीति संबंधी कोई भी निर्णय ये लोग मास्टर रामशरण के परामर्श से करते हैं और इस समय मास्टर रामशरण लोकदल-ब तथा जनता पार्टी के विलय के हामी हैं। ऐसी स्थिति में दोनों दलों के युवाओं के प्रयासों को रोक पाना दोनों ही नेतृत्वों के बस की बात नहीं है।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक विपक्ष के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भैरो सिंह शेखावत तो विपक्ष की एकता पर जवाब देने के लिए जयपुर में उपलब्ध नहीं थे, पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक भंवरलाल शर्मा का 'माया' से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी और दल में विलय का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हां, निश्चित कार्यक्रम के तहत विपक्ष की एकता के वह भी हामी हैं।

करिश्मों का चमत्कार : आज राजस्थान के हर विपक्षी दल को किसी करिश्में का इंतजार है। पिछले चुनावों के दौरान विपक्षी दल विधान सभा में अपना अस्तित्व करिश्में के कारण ही बचा पाये थे। लोकसभा के चुनावों में जिस तरह से वह कांग्रेस-इ से पराजित हुए थे, उस स्थिति में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विधान सभा में उनका नामलेवा भी कोई रहेगा। कांग्रेस-इ की लोकप्रियता का आलम यह था कि भाजपा का गढ़ समझे जानेवाले जयपुर शहर से सांसद नवल किशोर शर्मा जैसे कमजोर उम्मीदवार पचास हजार मतों से विजयी हुए थे। यह कटु सत्य है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने अगर शहंशाही रुख अपनाकर भरतपुर जिले के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिंह की हत्या का माहौल न बनाया होता, तो दो सौ सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में आज विपक्ष के ८५ के बजाय पांच प्रतिनिधि बैठे होते।

राजा मानसिंह की हत्या ने साख खोये विपक्ष को मतदाताओं के बीच पुनः विश्वास जमाने का अवसर दिया और उसी के परिणामस्वरूप ८५ सदस्य चुनकर पहुंचे। आज जब कांग्रेस-इ अपनी हैसियत खो रही है, तो विपक्ष की संभावना फिर से प्रबल हुई है। यह प्रबलता कार्यक्रम एवं नेतृत्व के अभाव में कल तक बेमानी थी, पर आज यह

लोकदल-ब की लोकप्रियता के साथ अर्थ पा रही है। इस लोकप्रियता के परिणामस्वरूप जहां जनता पार्टी के लोकदल में विलय का सवाल चर्चित हुआ है, वहीं भाजपा व अन्य दलों की सौदेबाजी की ताकत घटी है। नयी राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिणामस्वरूप आज राजस्थान में लोकदल-ब को छोड़कर बाकी सभी दल अपने वजूद के लिए वी० पी० सिंह की लोकप्रियता का दामन थामना चाहते हैं। उधर वी०पी० सिंह ने राजस्थान में प्रवेश के साथ जनता पार्टी और लोकदल-ब तक अपने को सीमित रखा है। इसका निश्चित असर राजस्थान की नम्बर दो पार्टी भाजपा पर पड़ा है। इस असर के परिणामस्वरूप विपक्ष के नेता और भाजपा के विधायक भैरो सिंह शेखावत को लोकदल के सम्मेलनवाली रैली में छुटभैय्यों की तरह शामिल होना पड़ा। वह बहुत साफ देख रहे हैं कि अगर मध्यावधि चुनाव हुए, तो लोकदल-ब के आसरे ही भाजपा राजस्थान में अपना अस्तित्व कायम रख पायेगी।

कांग्रेस-इ का विकल्प बन जाने की होड़ में लोकदल-अ पराजित होने के बावजूद लोकदल-ब से मोर्चा लेने की चेष्टा कर रहा है। लोकदल-ब के राजस्थान सम्मेलन के दौरान युवा लोकदल-अ के अध्यक्ष महिपाल सिंह यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल को पत्र लिख कर आरोप लगाया कि राजस्थान के लोकदल-ब सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हरिदेव जोशी सरकार जी-जान से जुटी हुई है। यादव ने मुख्यमंत्री देवीलाल को यह भी सलाह दी थी कि वह सम्मेलन के नौ-सूत्री संकल्पों के साथ-साथ श्री मिर्धा से यह आश्वासन भी दिलवायें कि वह भविष्य में किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के हकों के लिए लड़े जाने वाले किसी भी आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने की प्रवृति को बन्द करेंगे और राज्य सभा व राष्ट्रपति के चुनाव में गद्दारी करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

दरअसल प्रदेश लोकदल-ब अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा ने कई मौकों पर जोशी सरकार के क्रियाकलापों की प्रशंसा खुल कर की है। विपक्ष के किसी नेता का यह रुख आपातकाल के अतिरिक्त अरुचिकर लगता है। इसी तरह लोकदल-ब के विधायकों ने राज्य सभा के चुनावों के दौरान व राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपने व विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देने की बजाय सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को मत दिये हैं। इस अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्यवाही में श्री मिर्धा ने विशेष रुचि नहीं ली। यही वजह है कि लोकदल-ब के लोग उन पर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से सांठगांठ का आरोप लगाते हैं। बहरहाल, राजस्थान में लोकदल-ब कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर रहा है, भले ही इस उभार में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जाने-अनजाने मदद कर रहे हों।

छाया : गोपाल मेगर

—ओम सैनी

साक्षात्कार/ हेमवती नंदन बहुगुणा

राजीव चला जायेगा, तो जैसे रांड़ हो जायेगा देश!

माया : क्या विपक्ष सत्तारूढ़ दल का विकल्प खड़ा करने की स्थिति में है ? जनता आश्वस्त होना चाहती है कि विपक्ष राजीव गांधी की जगह स्थायी सरकार दे सकता है या नहीं ?

बहुगुणा : इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, जब तक जनता व्यक्ति ढूंढेगी देश की राजनीति पटरी पर नहीं बैठेगी। व्यक्ति ढूंढते हैं फासीवादी लोग, व्यक्ति ढूंढते हैं अलोकतांत्रिक लोग। लोकतांत्रिक लोग ढूंढते हैं, नीति और निष्ठा। व्यक्ति की खोज ने भारत को चालीस साल से गर्त में ही ढकेला है। इस घटिया विचारधारा में नया हिंदू नेतृत्ववाद छिपा है। जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर स्मिथ ने कभी एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों का मूल्यांकन कीजिए, तो पता चलेगा कि तीसरे दर्जे के लोग राज कर रहे हैं, सिवाय जर्मनी और जापान के। यह बात उन्होंने अहं भाव से नहीं कही थी। इसका कारण बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जर्मनी और जापान में जब तक दल का समर्थन न हो, कोई आदमी नेता नहीं बन सकता। जर्मनी में यह जरूरी होता है कि प्रमुख बनने वाले व्यक्ति ने कम-से-कम तीन महीने वित्त, उद्योग और विदेशी मामलों के विभाग देखे हों। राजीव ने एक साल बाद ही वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग अपने हाथ में ले लिया। उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ अभूतपूर्व बंद हुआ। अगर सरकार की आर्थिक नीतियां सही नहीं हैं, तो उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए थी। रट्टा मारकर पायलट बन गया, इससे ज्यादा था क्या वह ?

माया : आम चुनावों में तो राजीव गांधी को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला था ?

बहुगुणा : चुनाव में ५०० करोड़ रुपए खर्च किये थे इंका ने। ५० करोड़ तो अकेले इलाहाबाद में ही। मैं यह सब सिद्ध कर सकता हूं। इस देश की जनता को दिखायी नहीं देता, तो मैं क्या करूं। इंका के ४११ सदस्य जीते थे। ११ बाहर बाहर हो गये तो बचे ४००। अब ४०० में से ३९९ क्या गधे हैं ? नया नेता चुन लें अपना। राजीव ही पार्टी, राजीव ही नेता। हमारा राजीव से नहीं, इंका से रीति, नीति का झगड़ा है। राजीव चला जायेगा तो जैसे रांड हो जायेगा यह देश। हम कहते हैं, राजीव का जनादेश खतम हो गया है।

माया : यदि मध्यावधि चुनाव हुआ, तो आपकी क्या रणनीति होगी ?

बहुगुणा : हमारी रणनीति साफ है। हमने कहा था कि संसद गूंगी हो, तो सड़क पर बात करो। यदि मेरे देश के पत्रकार समझदार होते, तो मैं आज ही शुरू कर देता संघर्ष। पूरे देश को तैयार करना है। मैं मानता हूं साल-छह महीने हरियाणा पैटर्न पर आंदोलन चलाना होगा। जिस दिन पूरे देश से दस लाख लोग दिल्ली पहुंचेंगे, इंका सरकार का वही आखिरी दिन होगा। साल डेढ़ साल चलनें वाले इस संघर्ष से ही नेतृत्व उभरेगा।

माया : शायद अमिताभ फिर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं।

बहुगुणा : फिर जिता दीजिएगा उन्हें। कई लोगों ने मुझे पिछले चुनाव में सलाह दी कि मत लड़ो, मैं लड़ा। मैं कहीं बाहर भी लड़ने नहीं गया। मैं इलाहाबाद की जनता से पांच साल का समय और मांगूंगा। ■

BUSH
BUSH
2094
BUSH
9774
BUSH
BUSH
FULL REMOTE CONTROL
2096

आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के
तीन चेहरे. जिनमें परिपूर्णता के हैं रंग भरे.
हर एक बेजोड़. हर एक के साथ
इलेक्ट्रॉनिक कलर प्रेफ़रेंस कंट्रोल.
हर एक में है ब्लैक मैट्रिक्स कलर पिक्चर
ट्यूब. हर एक है बुश!

बुश— वह कंपनी जिसने ऑटोमेशन को
इलेक्ट्रॉनिक टेक्नालॉजी का
नया क्षितिज दिया. कंपनी जो है
सदा आगे... सितारों से आगे.

BUSH TV
सितारों से आगे.

Rediffusion/B/5537 d HI

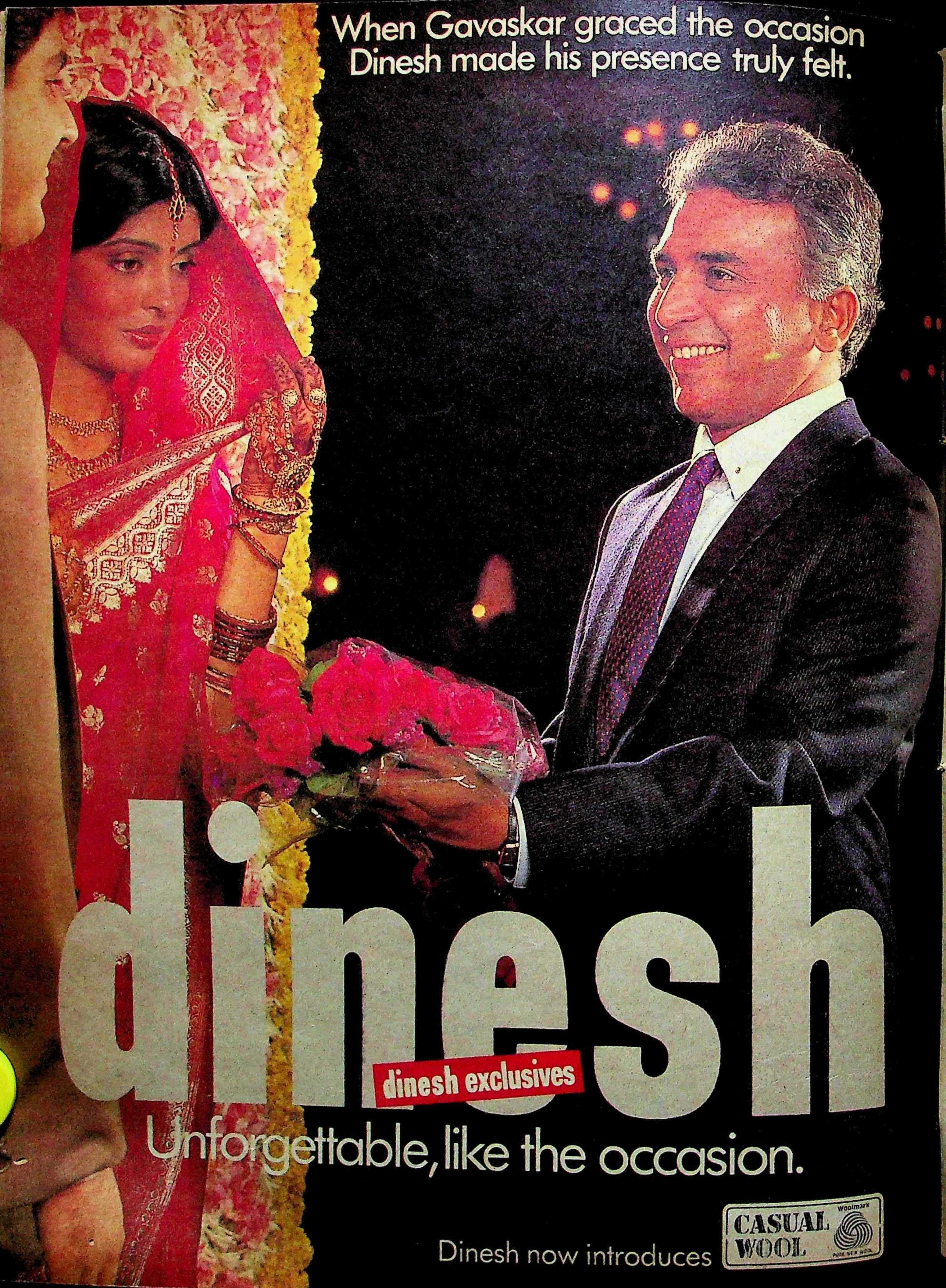
When Gavaskar graced the occasion
Dinesh made his presence truly felt.
dinesh
dinesh exclusives
Unforgettable, like the occasion.
Dinesh now introduces
CASUAL WOOL
Woolmark
PURE NEW WOOL

जिंदा दिल इंसान, अलबेला कलाकार

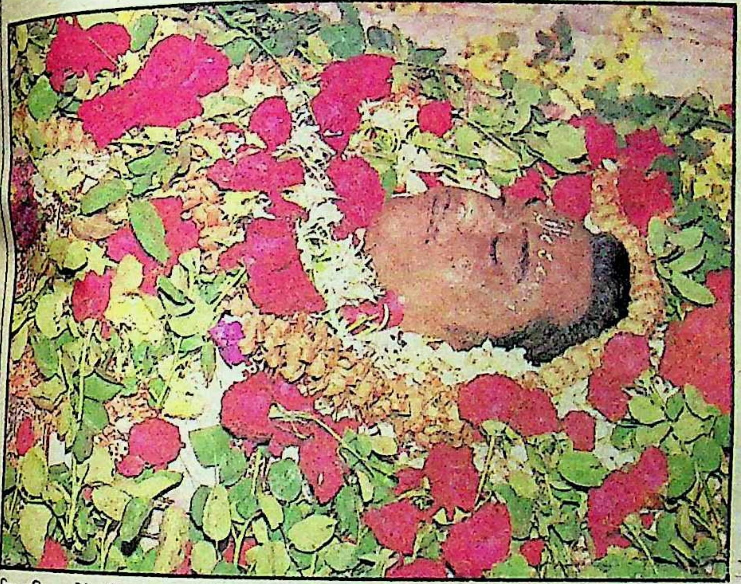

चिर निद्रा में लीन इस सदी का महान गायक किशोर कुमार छाया : दुर्गा प्रसाद

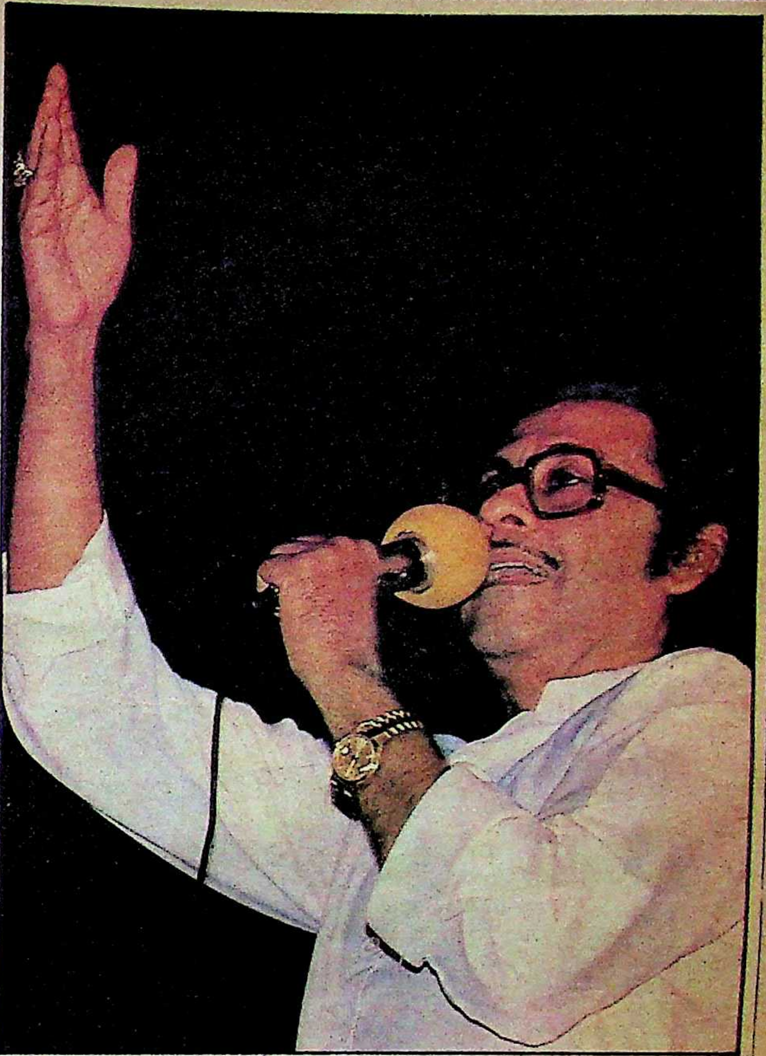

आवाज का जादूगर : किशोर कुमार छाया दुर्गा प्रसाद

पार्श्वगायन के क्षेत्र की यह तीसरी सबसे बड़ी क्षति है। १९७६ में मुकेश नहीं रहे थे और १९८० में मोहम्मद रफी को काल ने छीन लिया था। लेकिन १३ अक्तूबर, १९८७ को किशोर कुमार के असामयिक निधन से फिल्म क्षेत्र केवल एक गायक से ही नहीं, बल्कि एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार से वंचित हुआ है। प्रस्तुत है, किशोर कुमार की उन्मुक्त जिंदगी और बहुरंगी कला दुनिया की एक झांकी :

४० वर्ष पहले १९४८ में किशोर कुमार ने अपनी पहली फिल्म 'जिद्दी' के लिए 'मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे' गाया था, तो उन्हें क्या पता था कि मौत न तो दुआएं करने की मोहलत देती है और न ही जीने की तमन्ना पूरी करने का समय। लेकिन बिदांस कहे जाने वाले और मौत से हमेशा बेखौफ रहने वाले किशोर कुमार को १३ अक्तूबर को क्रूर मौत ने छीन ही लिया। वह भी उस दिन जिस दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्म दिन था।

किशोर कुमार अपने शयन कक्ष में पलंग पर चिरनिद्रा में थे और उनका पांच वर्षीय पुत्र सुमित 'डैडी उठो' की पुकार लगाता रहा। उस अबोध बालक को क्या पता था कि पिछले चार दशकों से लाखों-करोड़ों व्यक्तियों के दिलों पर अपने गायन का जादू करनेवाला और इस सदी का महान गायक अभिनेता, उसका पिता अब कभी नहीं उठेगा। वह तो महायात्रा के लिए निकल पड़ा है। हमेशा हंसते-मुस्कराते रहनेवाले दादा मुनि अशोक कुमार उतने शोक-संतप्त तब नहीं दिखलायी पड़े थे, जब कुछ ही महीने पहले उनकी धर्मपत्नी शोभा देवी का निधन हो गया था। वह सुमित को खींचकर सीने से चिपका लेते हैं।

"मुझे शाम को हैपी बर्थ डे कहने आनेवाला था," दादा मुनि सिसकने लगते हैं, "लेकिन मेरे घर का रास्ता भूल कर कहीं और चला गया निर्मोही ! कितना अभागा हूं मैं कि कुछ ही महीने के भीतर पहले शोभा मेरा साथ छोड़ कर चली गयी और अब किशोर। जाना मुझे था, चला गया वह। ऊपरवाला कितना कठोर है—सदमा देता है, तो देता ही चला जाता है एक-के-बाद-एक।" कुछ देर बाद उनकी आवाज संयत होती है। चश्मे के लेंस को साफ करते हैं, "जब भी स्टेज पर प्रोग्राम होता और इत्तिफाक से मैं मौजूद होता, तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले मुझे रंगमंच पर बुलाता, हजारों दर्शकों के बीच मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद मांगता। दर्शकों से मुखातिब हो कहता—"यह मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे पिता और गुरु हैं...इस उम्र में भी उसका बचपना, पागलपन नहीं गया था। मैंने तो बाकायदे शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन गाना आज तक मुझे नहीं आया, लेकिन किशोर तो संगीत का बिना क-ख-ग सीखे ही संगीतकार बन गया था। उसे सुर की सही समझ थी, इसीलिए वह हंगामें भी सुर में ही किया करता था, सुर में ही उछलता-कूदता था।"

"दिनभर वह ठीक-ठाक थे," किशोर की

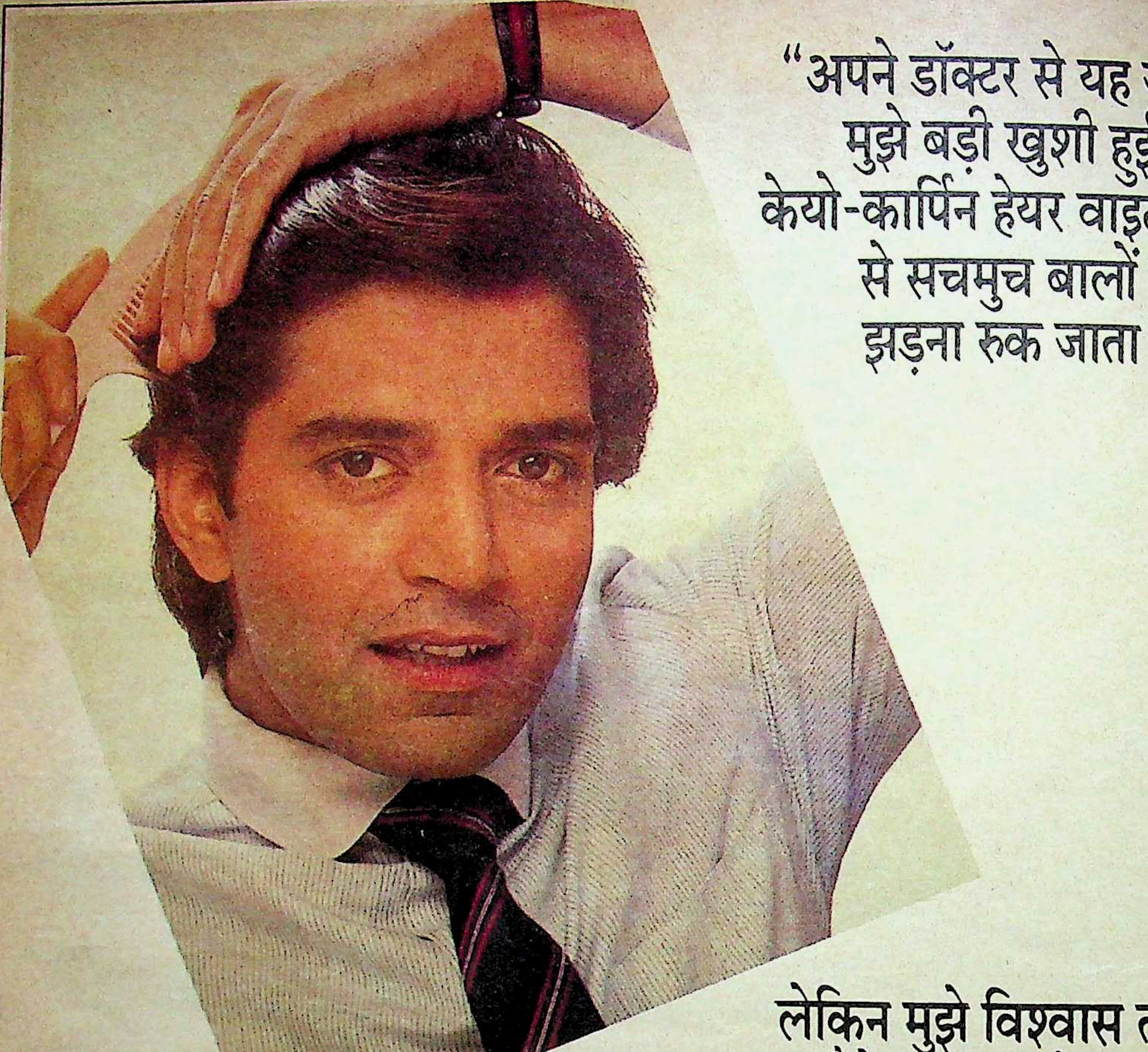

"अपने डॉक्टर से यह जानकर
मुझे बड़ी खुशी हुई कि
केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र
से सचमुच बालों का
झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ
जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढिया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Dey's
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER

बालों का झड़ना रोकने का
प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह श्रृंगार सामग्री नहीं है।

CLARION C-DMKV-4

पत्नी लीना चंदावरकर बतलाती हैं, "दिन में अमित (किशोर कुमार का बड़ा पुत्र) के ट्रंककाल का इंतजार करते रहे। सोये भी, सुमित (छोटा पुत्र) के साथ खेले भी। कहा—'शाम को दादा के घर (चेंबूर) चलकर उनका जन्म दिन मनायेंगे। शाम को ४.३० बजे उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। गंभीर दौरा नहीं था, जैसा कि पहले (१९८१ एवं १९८२ में) पड़ा था। लेकिन बेहोश होकर गिर पड़े। न ही दर्द से कराहे और न ही कुछ बोल पाये, जबकि इसके पहले के दौरों के समय वह जोरों से कराहे भी थे और देर तक सीने में दर्द के कारण छटपटाते भी रहे थे। इस बार जो बेहोश हुए, तो अंत तक होश में नहीं आ पाये।"

दिल का दौरा पड़ते ही पारिवारिक चिकित्सक डा० मणि कांगा और दूसरे हृदय रोग विशेषज्ञों को सूचित किया गया, जब तक वे पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत ने उन्हें न बात करने की मोहलत दी और न ही कुछ देर जी लेने की।

जिंदादिली : ५८ वर्ष की उम्र में भी वह जिंदादिल थे। गाने के कार्यक्रम के समय रंगमंच पर पहुंचते ही वह भूल जाते कि वह दिल के मरीज हैं, उछलना-कूदना जानलेवा हो सकता है। हमेशा साथ रहनेवाला डाक्टर उन्हें रोकता, पास बैठी पत्नी लीना चंदावरकर उन्हें बरजती, लेकिन संगीत की धुन उन्हें पागल बना देती और वह बरजते-रोकते डाक्टर तथा पत्नी को यह कहते हुए 'हूट' कर देते—"देखो, देखो, वह बैठी है मेरी पत्नी और वह रहा मेरा डाक्टर—दोनों मुझे आंखों-आंखों से डांट रहे हैं कि मैं उछलूं-कूदूं नहीं !" और वह 'अरे ऐसा तो मैंने नहीं कहा था' वाला गाना और भी तेजी से नाचते-उछलते हुए गाने लगते। धीरे-धीरे उनकी हांफनी बढ़ जाती। तब भी वह मंच से नहीं हटते, तो मजबूरन लीना चंदावरकर और डाक्टर को रंगमंच पर आना पड़ता या लीना बेटे सुमित को आगे कर देती और सुमित से असीम प्यार करनेवाले किशोर चुपचाप उसके साथ रंगमंच से बाहर चले आते और बड़ा बेटा अमित मंच संभाल लेता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद 'पगहा छुड़ा कर' वह तुरंत भाग कर मंच पर पहुंच जाते और माइक अपने हाथ में लेकर धमाचौकड़ी शुरू कर देते।

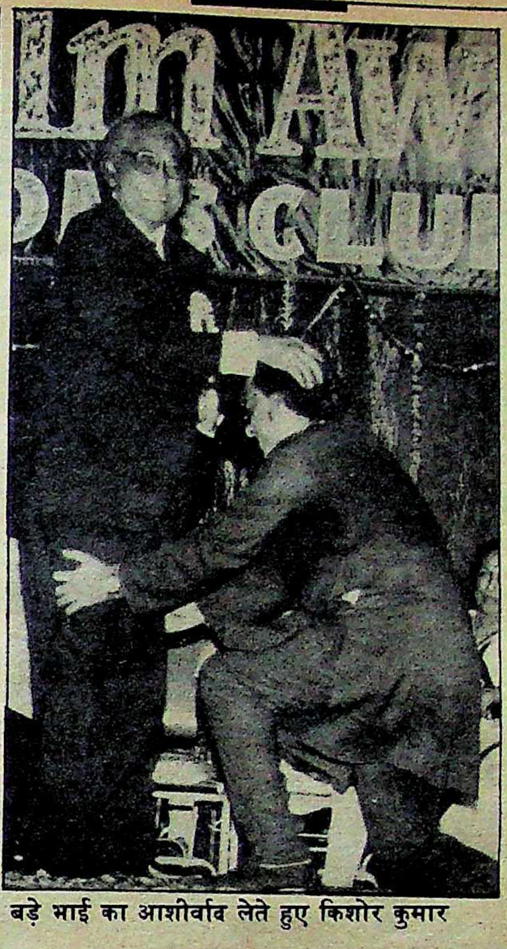

बड़े भाई का आशीर्वाद लेते हुए किशोर कुमार

चार-चार शादियां : 'कुएं में कूद कर मर जाना, यार तुम शादी मत करना' गानेवाले किशोर के भाग्य में चार-चार पत्नियां (रूमा देवी, मधुबाला, योगिता बाली तथा लीना चंदावरकर) और लीना के भाग्य में दो-दो बार वैधव्य लिखा हुआ था। चार-चार शादियों की बात चलने पर वह अपना ही गाया एक पुराना गीत 'शादी किस्मत की बात है, मालिक के हाथ है' सुना दिया करते थे। लेकिन किशोर ने कभी भी अपनी किसी भी पत्नी से बेवफाई नहीं की थी और न ही खुद किसी को छोड़ा था। एक बार मधुबाला से उनके एक दोस्त ने पूछा—'तुमने क्या देखकर इस 'मसखरे-पगले' से शादी की थी ? किस बात पर उस पर इस तरह रीझ गयी थी कि उसके लिए सारा कुछ त्याग दिया था ?' मधुबाला ने जो जवाब दिया था वही दो दशक बाद, यही सवाल पूछने पर, लीना ने भी जवाब दिया था, "उनके बारे में हमेशा लोगों को भ्रम रहा है। न तो वह पागल हैं और न ही मसखरे। वह मन से मूडी और बिंदास हैं। एक जगह स्थिर चित्त होकर वह बैठ नहीं सकते। कुछ-न-कुछ हरकत वह करते ही रहेंगे। यहां तक कि वह बहुत गंभीर हुए, तो भी वह चुप नहीं बैठ सकते। वह पानी की तरह निश्छल, रेशम की तरह मुलायम दिल, मक्खन की तरह नरम और बच्चों की तरह सहज-सरल हैं। उनके इसी व्यवहार से लड़कियां उनके पीछे पागलों की तरह घूमती थीं।" लगभग ऐसी ही या इससे मिलती-जुलती बात योगिता बाली ने १९७५ में किशोर से विवाह के तत्काल बाद पत्रकारों से कही थी।

४० वर्ष पहले १९४८ में किशोर कुमार ने अपनी पहली फिल्म 'जिद्दी' के लिए 'मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे' गाया था, तो उन्हें क्या पता था कि मौत न तो दुआएं करने की मोहलत देती है और न ही जीने की तमन्ना पूरी करने का समय। लेकिन बिंदास कहे जाने वाले और मौत से हमेशा बेखौफ रहने वाले किशोर कुमार को १३ अक्तूबर को क्रूर मौत ने छीन ही लिया।

निराला ढंग : किशोर का बिंदासपना जहां दर्शकों को गुदगुदाता था, वहीं गाने में एक विशेष आलम भर देता था। रिकार्डिंग के लिए वह जब जाते, तो फिल्म-निर्माता की मुसीबत होती थी, क्योंकि दूसरे गायकों की तरह अपनी जगह खड़े रहकर गा नहीं सकते थे। साउंड रिकार्डिस्ट की 'सांग स्टार्ट' की आवाज सुनायी पड़ते ही वह गाने के बोल के साथ उछल-कूद शुरू कर देते, कभी-कभी तो जमीन पर लेट जाते। उनकी इस आदत को ध्यान में रखकर उनके लिए माइक की विशेष व्यवस्था की जाती, सिर्फ एक आदमी रिकार्डिंग कक्ष के बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता कि कहीं मौका पाकर वह भाग नहीं निकलें, क्योंकि ऐसा अकसर होता रहता था और उस बात के लिए वह बदनाम भी काफी हो गये।

कुछ महीने पहले बप्पी लाहिड़ी के एक गाने की रिकार्डिंग बीच में छोड़कर चले आये, तो फिल्म इंडस्ट्री में काफी हंगामा मचा। इसकी चर्चा चलने पर उन्होंने कहा था—"शोभा भाभी की मौत से मैं बहुत ही मर्माहत था। बप्पी लाहिड़ी जो गाना रिकार्ड करना चाहते थे, वह छेड़छाड़ और कामेडी मूड का गाना था। उस तरह के गाने का मेरा मूड ही नहीं बन पा रहा था। अगर सीरियस गाना होता, तो मैं काफी अच्छे ढंग से उसे गा देता। मैंने बप्पी लाहिड़ी से अपनी समस्या बतलायी और वापस लौट आया कि बाद में उस गाने की रिकार्डिंग करूंगा। लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि अगर मैं किसी गाने को गाने से ना-नुकुर करता हू या उनके न मानने पर कोई बहाना निकाल कर भाग जाता हूं, तो उसका कोई कारण तो होगा।"

इस बात को न तो फिल्म-निर्माताओं ने कभी समझने की कोशिश की, न ही इसे स्पष्ट करने की किशोर कुमार ने जरूरत महसूस की। फलतः किशोर कुमार तरह-तरह के किस्सों के केंद्र बन गये। वह लता मंगेशकर की तरह अपनी कीमत में एक पैसा कम नहीं करते थे और गाने के पहले पूरा पारिश्रमिक ले लेते थे। इस बात को लोगों ने तरह-तरह की किंवदंतियां बना कर जोर-शोर से प्रसारित कर दिया। एक किंवदंती है—किशोर कुमार ने 'स्टार्ट साउंड' की आवाज होते ही कांच के बाहर खड़े अपने सेक्रेटरी-कम-ड्राइवर अब्दुल्ला की ओर देखा, लेकिन उस तरफ से कोई हरकत नहीं हुई और अचानक वह धम से जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गये। जब होश में लानेवालों में किसी ने जूता सुंघाने की पेशकश की, तो अब्दुल्ला ने धीरे से फिल्म-निर्माता के कान में फुसफुसाया—'जूता नहीं, नोटों की थप्पी (गड्डी) सुंघाओ, अभी होश [illegible] जायेगा।'

बेचारा प्रोड्यूसर सारी चाल समझ गया, माथा पीट लिया। उसी वक्त सेट से भागा और दो

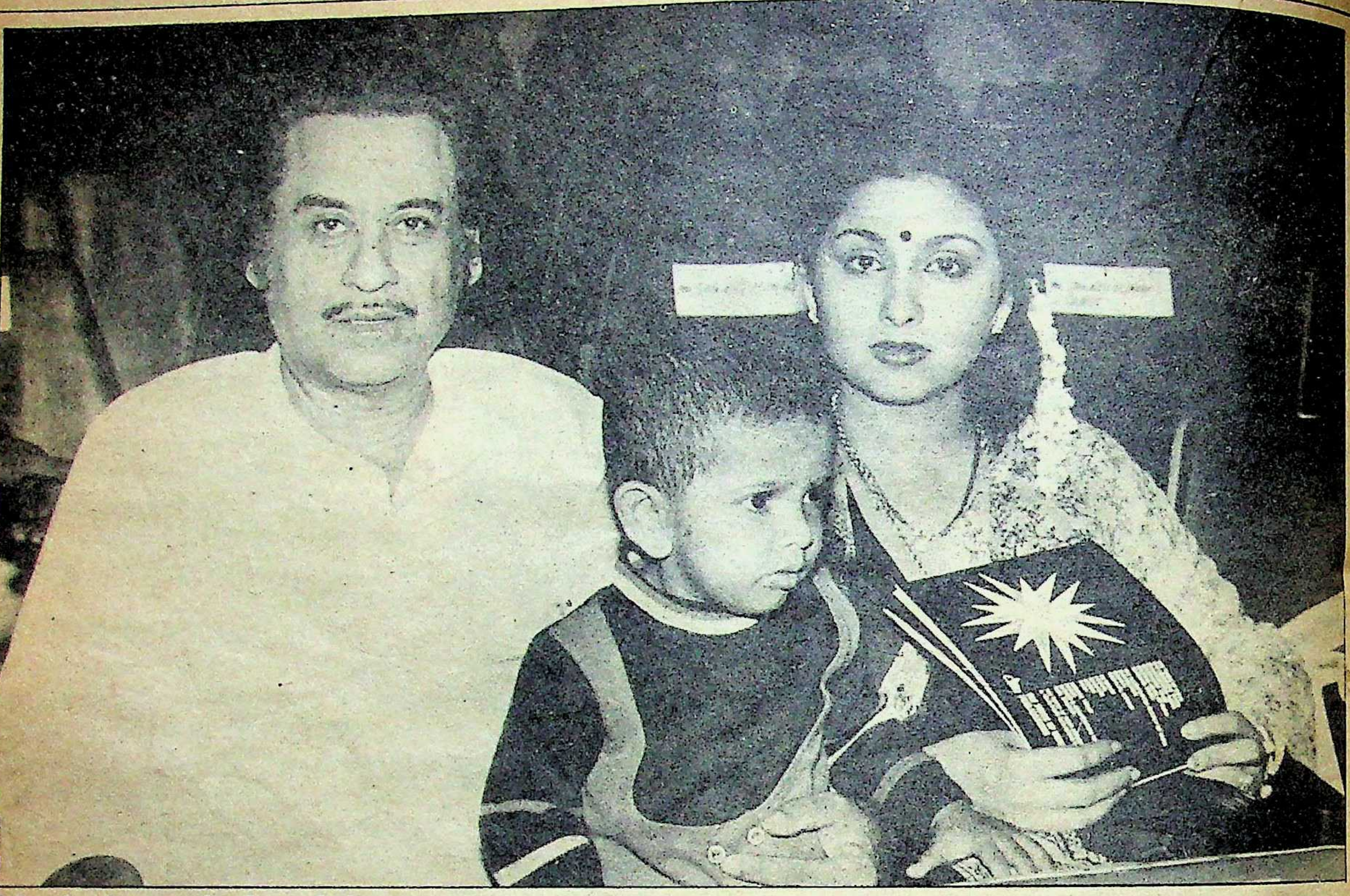

चौथी पत्नी: लीना, पुत्र सुमित के साथ किशोर कुमार

घंटे बाद नोटों की मोटी गड्डी लेकर लौटा। तब तक किशोर कुमार सेट से अपने मेकअप रूम में जा चुके थे और आराम फरमा रहे थे। प्रोड्यूसर ने गड्डी हाथ में दी, तो फूल की तरह सूंघने लगे, आ हा हा...अब तबीयत ठीक मालूम पड़ती है। तुम चलो आता हूं सेट पर...।"

चुलबुलापन: बचपन से ही बेहद शरमीले किशोर अचानक इतने चंचल-चुलबुले कैसे बन गये, इसका पता न तो आज तक किशोर के बचपन के दोस्त ढूंढ़ पाये, न ही उनके परिवार के लोग। एक बार किशोर ने एक मजेदार बात 'माया' को बतलायी थी—"जिद्दी के युगल गाने की 'रिकार्डिंग' के लिए मैं और लताजी लोकल ट्रेन के एक ही डिब्बे में जा रहे थे। दोनों एक-दूसरे को पहचानते नहीं थे। मैंने लताजी को देखा, उन्होंने मुझे देखा और आंखें झुका लीं। यह हरकत कई बार हुई। मलाड स्टेशन पर उतरकर वह एक तांगे पर सवार हुईं। बांबे टाकीज पहुंचकर उन्होंने मुझे एक दूसरे तांगे से उतरते देखा, तो बहुत नर्वस हुईं। बस, मजा आ गया।" लताजी जब भी मिलतीं, किशोर उन्हें उस घटना की याद दिला कर चिढ़ाते, तो वह मुस्करा पड़तीं। लेकिन १४ अक्तूबर को लताजी ने किशोर के शव को देखा, तो इतनी मर्माहत हुईं कि खड़े रहने के लिए उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ा और घर वापस आकर चारपाई पर पड़ गयीं।

मूलतः गायक: किशोर अपने को मूलतः गायक मानते थे, अभिनेता नहीं। अभिनय की बात चलने पर कह देते, "इसे आप अभिनय कहते हैं? यह तो भड़ैती है।" वह अपने गाये प्रिय गानों में 'दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना' (फंटूश), 'चिंगारी कोई भड़के' (अमर प्रेम), 'आ चल के तुझे मैं ले के चलूं, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हों' तथा 'जिंदगी का सफर, है यह कैसा सफर' (सफर) का शुमार करते। अकसर कल्याणजी को हूट करते, "अरे, इस जिंदगी में कुछ अच्छी धुनें बना लो कल्याणजी भाई। जिंदगी तुम्हारी भी संवर जायेगी और मेरी भी।" लेकिन हर बात वह मजाकिया लहजे में ही कहते।

खंडवा के प्रख्यात एडवोकेट कुंजलाल गांगुली के तृतीय पुत्र आभास कुमार उर्फ किशोर कुमार गांगुली (जन्म: ४ अगस्त, १९२९, समय: ४ बजे) की शिक्षा खंडवा में बांबे बाजार प्राइमरी स्कूल तथा न्यू हाई स्कूल और इंदौर में क्रिश्चियन कालेज में हुई। १९४९ में कुंदन लाल सहगल, जिन्हें वह बचपन से ही एकलव्य की तरह गुरु मान बैठे थे और उनके गानों को कालेज कार्यक्रमों के अलावा भी बड़े तरन्नुम से गाया करते थे, से मिलनें की इच्छा लेकर वह बंबई आ पहुंचे जहां उनके बहनोई शशधर मुखर्जी सबसे प्रख्यात निर्माता तथा बड़े भाई अशोक कुमार स्टार बन चुके थे।

१९४९ मे बांबे टाकीज की फिल्म 'जिद्दी' के संगीत निर्देशक स्व० खेमचंद प्रकाश ने जब उन्हें गुनगुनाते सुना तो बुलाकर कुछ गाने गवाये। अशोक कुमार के मना करने के बावजूद कि 'अरे यह तो यूं ही ही-ही-हू-हू करता है, कभी संगीत की कोई भी तालीम नहीं ली' उन्होंने किशोर कुमार की आवाज में पहला गाना 'मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे' गवाया। 'जिद्दी' (निर्देशक: शाहिद लतीफ) के लिए लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत 'ये कौन आया रे' गवाया। उन्होंने 'जिद्दी' में माली की एक्स्ट्रानुमा भूमिका भी निभायी।

अशोक कुमार के घर अकसर आनेवाले उनके मित्र फणि मजुमदार तथा पी०एल० संतोषी को किशोर की हरकतें कुछ इस तरह भायीं कि उन्होंने उन्हें अभिनेता बना दिया—फणि मजूमदार ने अपनी डाक्युमेंटरी फिल्म 'आंदोलन' (१९५१) तथा पी०एल० संतोषी ने फीचर फिल्म 'छम छमा छम' (१९५२) में मुख्य भूमिका दी, लेकिन किशोर की पहचान बनी ए०वी०एम० की फिल्म 'लड़की' (१९५३) से, जिसके निर्देशक थे एम०वी० रामन, जिन्हें किशोर कुमार अपना 'फ्रेंड, फिलास्फर एवं गाइड' कहकर परिचय कराया करते थे। उन्होंने एम०वी० रामन निर्देशित फिल्म 'पहली झलक,' 'भाई-भाई,' 'आशा,' 'चंदन,' 'पायल की झंकार' आदि फिल्मों में भी काम किया। जिद्दी के निर्देशक शाहिद लतीफ ने उन्हें 'फरेब' (१९५३) में बतौर नायक पेश किया।

१९५२ के बाद किशोर कुमार का जो

सितारा चमका तो अगले दस वर्षों तक वह अगली पांत के अभिनेता बने रहे। १९५३ में तीन, १९५४ में छह, १९५५ में तीन, १९५६ में सात, १९५७ में पांच, १९५८ में चार, १९५९ में तीन, १९६० में चार, १९६१ में उनकी एक तथा १९६२ में पांच फिल्में प्रदर्शित हुईं। हर वर्ष उनकी फिल्में बाक्स आफिस पर हिट होती रहीं और उन्होंने इस दौरान लगभग हर बड़े निर्देशक के साथ काम किया, इनमें प्रमुख थे—आर०सी० तलवार (इल्जाम; रुखसाना, मेम साहब आदि) फणि मजूमदार (आंदोलन, धोबी डाक्टर), ए०आर० कारदार (बाप-रे-बाप) एल०बी० प्रसाद (मिस मेरी), विमल राय (नौकरी), मोहन सहगल (अधिकार, नयी दिल्ली, अपना हाथ जगन्नाथ, करोड़पति), सत्येन बोस (बंदी, दाल में काला, गर्ल फ्रेंड, चलती का नाम गाड़ी), एच०एस० रवेल (लहरें, शरारत), ऋषिकेश मुखर्जी (मुसाफिर), के० अमरनाथ (नया अंदाज), एस०डी० नारंग (दिल्ली का ठग, बांबे का चोर) कृष्णन पंजू (मनमौजी), अमरकुमार (रंगोली), शक्ति सामंत (नाटी ब्वाय, एक राज) इनके अलावा उस जमाने के जाने-माने हास्य अभिनेताओं द्वारा निर्देशित उनकी फिल्मों 'भागमभाग' (भगवान, १९५६), 'चाचा जिंदाबाद' (ओमप्रकाश, १९५९), 'बेवकूफ' (आई०एस० जौहर, १९६०), 'बागी शाहजादा' (मारुति, १९६४), और हम सब उस्ताद हैं में भी काम किया।

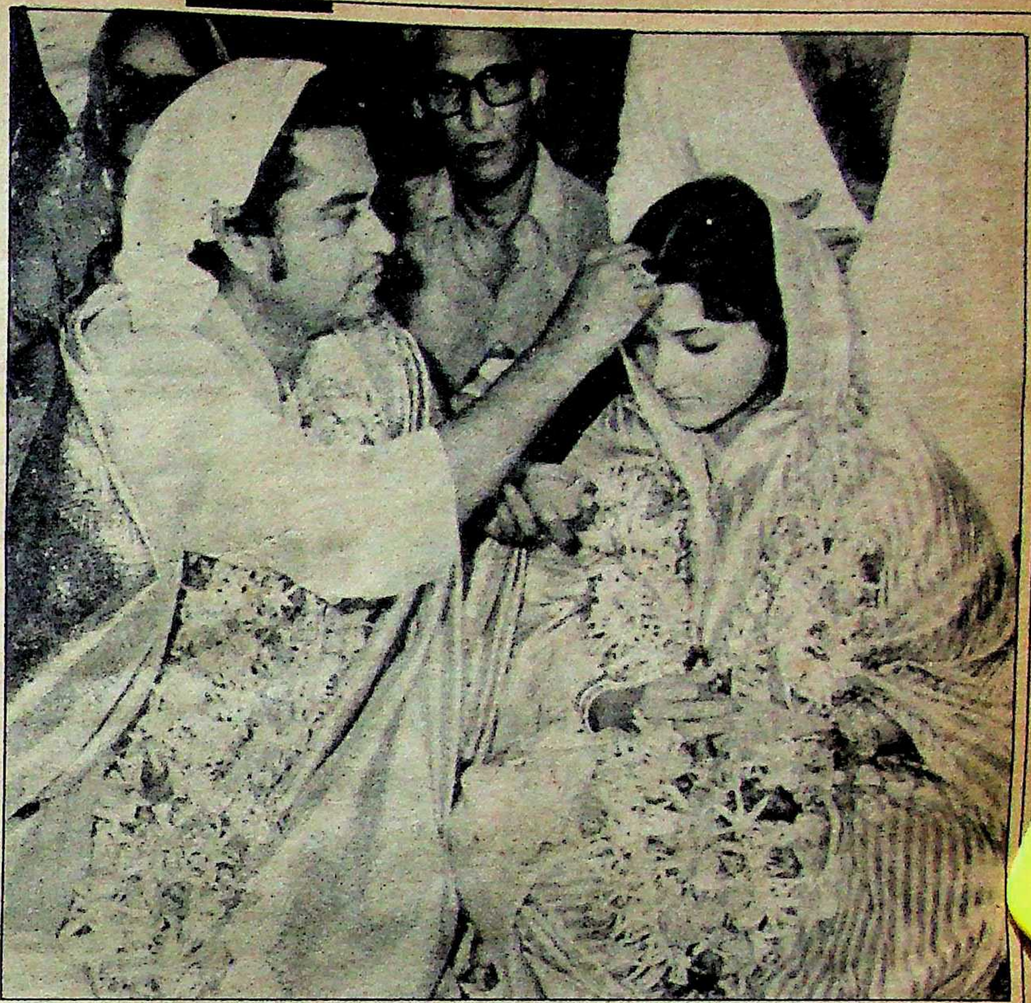

तीसरा ब्याह: किशोर कुमार योगिता बाली की मांग भरते हुए

भाई के बिछोह से व्यथित: अशोक कुमार और अनूप कुमार

किशोर कुमार की उछल-कूद अभिनय शैली को एक अनोखे ढंग से एंग्रीमैन का रूप देकर शम्मी कपूर जो फिल्मों में अवतरित हुए, उसका असर किशोर कुमार के कैरियर पर भी पड़ा। कुछ फिल्मों की व्यावसायिक असफलता तथा कुछ उनकी बिंदासपना लापरवाह हरकतें, सभी बड़े निर्माता-निर्देशक एक-एक कर उनके दायरे से खिसकते चले गये। इसी बीच आयकर विभाग के छापों के दौर ने भी उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर डाला। साथ ही किस्मत ने भी उन्हें कम परेशान नहीं किया। १९६२ के बाद उनकी सभी फिल्में ('प्यार किये जा' को छोड़कर) बाक्स आफिस पर बुरी तरह से पिटीं और उन्हें द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की फिल्मों में काम करने के लिए विवश होना पड़ा। १९७३ में प्रदर्शित 'प्यार दीवाना' उनकी अंतिम बाहर की फिल्म थी। १९६३ से १९७३ के बीच वे फिल्में प्रदर्शित हुई थीं, जिन्हें उन्होंने शुरू में बिना सोचे-समझे साइन कर लिया था। तब ये श्वेत-श्याम फिल्में थीं। १९६१ के बाद रंगीन फिल्मों ने श्वेत-श्याम फिल्मों का डिब्बा गुल कर दिया।

गायन की शुरूआत: यह भी इत्तिफाक था कि जिस शक्ति सामंत की घटिया फिल्म 'एक राज' (१९६३) से किशोर कुमार का अभिनय कैरियर अंधेरे में गुम हो गया, लगभग एक दशक बाद उस शक्ति सामंत की फिल्म 'आराधना' से पार्श्व गायक के रूप में जो वह अवतरित हुए तो पार्श्व गायन के

पार्श्वगायनं के क्षेत्र का एक सितारा टूट गया: आर०डी० बर्मन, लता और आशा के साथ किशोर कुमार

८०० से भी अधिक फिल्मों में लगभग दस हजार गाने गाये। उन्होंने सबसे अधिक गाने गाये एस०डी० बर्मन तथा आर०डी० बर्मन के लिए और सबसे कम नौशाद के लिए। उनके गानों ने दर्शकों को ठहाके लगाने के लिए मजबूर किया, तो रोने के लिए भी। वह अकेले गायक थे जिनके गाने पर सिनेमा हाल और थियेटर में दर्शक खड़े होकर साथ-साथ नाचने-गाने लग जाते थे। वे सबसे महंगे पार्श्व गायक थे।

अभिनय: उनकी अभिनीत फिल्मों में नयी दिल्ली, भाई-भाई, आशा, लुको चोरी (बंगला में खुद की निर्मित फिल्म) ने स्वर्ण जयंती, अधिकार, लड़की, पहली झलक, प्यार किये जा, दिल्ली का ठग, इलजाम, चंदन, बेवकूफ, शरारत तथा चलती का नाम गाड़ी (खुद की निर्मित) ने रजत-जयंती मनायी।

नायिकाएं: किशोर कुमार की प्रथम नायिका थीं—रेहाना (छम छमा छम) तथा अंतिम नायिका थीं, पत्नी लीना चंदावरकर ('ममता की छांव में' तथा 'प्यार अजनबी है') लेकिन सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया वैजयंती माला (लड़की, मिस माला, पहली झलक, नयी दिल्ली, आशा, रंगोली आदि), मधुबाला (ढाके की मलमल, महलों के ख्वाब, हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, सुहाना गीत आदि) तथा मीना कुमारी (इलजाम, मेमसाब, नया अंदाज, मिस मेरी, शरारत, रुखसाना आदि) के साथ। इनके अलावा उषा किरण (अधिकार, धोबी डॉक्टर,

सभी समीकरण बंदल दिये। जिस मोहम्मद रफी के बारे में कहा जाता था कि 'लता तो और भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन रफी के विकल्प की कल्पना ही नही की जा सकती' उसी रफी सहित मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर को किशोर ने व्यावसायिक पर्दे से इस कदर दरकिनार कर दिया कि उन्हें व्यस्त रहने के लिए देश-विदेश में संगीत-कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ा। दिलीप कुमार, संजीव कुमार, स्मिता पाटील आदि की तरह वह अभिनय के मैदान में झंडा तो नहीं गाड़ पाये, लेकिन पार्श्वगायन में उन्होंने अपनी गायन वैविध्यताओं के इतने कीर्तिमान कायम किये कि उन्हें सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गायन के फिल्मफेयर व बंगला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन के सात-सात पुरस्कार, लायंस क्लब आफ बांबे के लगातार १४ पुरस्कार जीते और ई०एम०आई० ने लासएंजिलेस में एक विशेष समारोह कर उन्हें 'गोल्डन डिस्क' प्रदान की।

किशोर कुमार ने चार दशकों में सभी पीढ़ियों के जाने-माने संगीतज्ञों स्व० खेमचंद्र प्रकाश, अनिल विश्वास, पन्ना लाल घोष के अलावा एस०डी० बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ०पी० नैयर, मदन मोहन, सलिल चौधरी, सी० रामचंद्र, हेमंत कुमार, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर०डी० बर्मन, कल्याणजी आनंदजी, भप्पी लाहिड़ी के साथ

हर दिल अजीज कलाकार: किशोर कुमार और निम्मी

मुसाफिर आदि), बीना राय (मदभरे नैन, बंदी), माला सिन्हा (बेवकूफ, चंदन, पैसा ही पैसा, बांबे का चोर, लुको-चोरी आदि), नूतन (चंदन, दिल्ली का ठग, कभी अंधेरा, कभी उजाला) के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों ने काफी पसंद की। नूतन की ये तीनों फिल्में १९५८ में प्रदर्शित हुई थीं।

बंगला अभिनेत्री रूमा देवी को छोड़कर उनकी अन्य तीनों पत्नियां उनके साथ फिल्म में काम करते समय उन्हें अपना दिल दे बैठीं और अंततः विवाह कर लिया। १९५६ में 'ढाके की मलमल' में पहली बार किशोर कुमार के साथ काम करते समय मधुबाला उनकी तरफ आकर्षित हुईं। इस आकर्षण का ही परिपाक था कि १९५८ में किशोर ने मधुबाला को लेकर 'चलती का नाम गाड़ी' तथा मधुबाला ने १९६० में किशोर कुमार को लेकर 'महलों का ख्वाब' का निर्माण किया और दोनों परिणय सूत्र में बंध गये। किशोर की तीसरी पत्नी योगिता बाली 'शाबास डैडी' के समय किशोर को अपना दिल दे बैठी। यही हाल लीना का एक फिल्म निर्माण-योजना के समय हुआ जो अब तक बनी ही नहीं।

किशोर कुमार ने 'चलती का नाम गाड़ी' तथा 'लुको-चोरी' (१९५८), झुमरू (१९६१), दूर गगन की छांव में (१९६४), हम दो डाकू (१९६७), दूर का राही (१९७२), बढ़ती का नाम दाढ़ी (१९७४), शाबास डैडी (१९८०), चलती का नाम जिंदगी (१९८१); दूर वादियों में कहीं (१९८३) का निर्माण किया। इनमें से प्रथम दो को छोड़कर शेष सभी फिल्मों के निर्देशन से लेकर पटकथा लेखन तक के सारे काम उन्होंने खुद निबटाये। 'चलती का नाम गाड़ी' को छोड़कर शेष सभी फिल्मों का संगीत खुद दिया और गीत भी लिखे। 'ममता की छांव में' तथा 'प्यार अजनबी है' फिल्में अधूरी बनी पड़ी हैं। 'सुहाना गीत' (निर्देशक : फणि मजूमदार) का निर्माण मधुबाला के असामयिक निधन के कारण बीच में ठप्प पड़ गया था। इनके अलावा उन्होंने 'दिल्ली की बिल्ली, बंबई का बिल्ला' तथा 'दीनू का दीनानाथ' बनाने की भी घोषणा की, जो बन नहीं सकी।

बहुमुखी प्रतिभा: किशोर कुमार एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार थे। १९५० के दशक से ही किशोर ने 'छम छमा छम,' 'नौकरी,' 'रुखसाना,' 'भाई भाई,' 'बहार' फिल्मों के जरिये अभिनय के क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया था।

१९४० के दशक के हास्य अभिनेता फिल्मी परदे से उतर चुके थे और फिल्मी-दर्शक गोप, मारुति, आगा और भगवान की कामेडी में रस नहीं ले पा रहे थे, तभी युवा किशोर ने कामेडी के क्षेत्र में प्रवेश किया और देखते-ही-देखते लोकप्रिय हो गये।

किशोर कुमार के हास्य की खासियत यह थी कि वह अपने समय के हास्य अभिनेताओं आगा, राजेंद्र नाथ, जानी-वाकर और महमूद के बेतुके और फूहड़पन से भरे अभिनय से हमेशा अपने को अलग करते रहे। किशोर हास्य को मौलिकता में पेश करते थे। राजसी रोबदाब, संभ्रांतता या बुजुर्गियत की नकल करना और अजीबोगरीब आवाजें निकालने में उनका कोई सानी नहीं था।

अभिनय और गायन का मिलाजुला उत्कर्ष है, किशोर की फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी'। 'चलती का नाम गाड़ी' हिंदी की सबसे बड़ी कामेडी फिल्म मानी जाती है।

किशोर ने जीवन भर कामिडी फिल्में कीं और अधिसंख्य आनंद भरे गीत गाये। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपने फिल्मकार और संगीतकार को गंभीरता से नहीं लिया।

किशोर की हार्दिक आकांक्षा थी, अपने गुरु स्व० कुंदनलाल सहगल के अमर गीतों को अपनी आवाज में रिकार्ड करायें। एच०एम०वी० वालों से बात भी हो चुकी थी कि नवंबर में सहगल के १३ गीतों का अलबम वह रिकार्ड करायेंगे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी।

किशोर कुमार हमेशा कहा करते थे, "मैं खंडवा में पैदा हुआ—अच्छा-भला इंसान था, यहां आकर गीतों का, कला का व्यापारी बन गया। मैं चाहता हूं, मेरे अंतिम दिन खंडवा में बीतें, वहीं की धरती पर पैदा हुआ, वहीं पर मेरी चिता भी बने।" उनकी इच्छानुसार उनका शव एक विशेष वातानुकूलित एबुलेंस से, जिसकी व्यवस्था शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने की थी, १५ अक्तूबर को खंडवा ले जाया गया।

किशोर की मौत के समय बड़ा पुत्र अमित टोरंटो (कनाडा) अपने दल के साथ संगीत कार्यक्रम पेश कर रहा था, पहले इस दल के साथ किशोर कुमार भी जानेवाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। नवंबर में ही अमित की शादी होनेवाली थी। १९८१-८२ में अमित की शादी जिस लड़की से उनकी प्रथम पत्नी रूमा गुहा ने तय की थी, ऐन वक्त पर, किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ने के कारण वह स्थगित हो गयी थी। रूमा ने आइंदा किशोर से भेंट न करने की कसम खायी थी, लेकिन उन्हें कसम तोड़कर १४ अक्तूबर की रात को कलकत्ता से बंबई आना पड़ा था—अपने प्रथम पति को, जो फूलों की चादरों के नीचे चिरनिद्रा में सोया हुआ था, अंतिम विदा देने के लिए।

गायक के रूप में किशोर कुमार की अपनी अद्भुत क्षमताएं थीं। उनकी आवाज में सुरीलेपन के साथ-साथ मनोरंजन के वे राग भरपूर हैं जो श्रोता के कानों की राह से मन में उतरने की पूरी क्षमता रखते हैं। आवाज में एकरसता तो कतई नहीं है, साथ ही कुछ ऐसा वैविध्य है जो पूर्ववर्ती गायकों में मोहम्मद रफी के अलावा किसी गायक में न था। वह कैसी भी आवाज मुंह से निकालें, सुरीली लगती है। यही कारण है, स्टेज कार्यक्रमों में किशोर ने अद्भुत सफलता अर्जित की।

वाकई अद्भुत ही हैं, किशोर। संगीतकार ओ०पी० नैयर का कहना है, "लता और आशा जैसी गायिकाएं कभी भी पैदा हो सकती हैं, मगर किशोर कुमार जैसा गायक कभी पैदा हो सकेगा, कहना बहुत 'मुश्किल है...।"

—रवींद्र श्रीवास्तव,
हरीश तिवारी

छाया : दुर्गा प्रसाद, डी०आर० यादव

दूसरी पत्नी : 'झुमरू' में किशोर कुमार और मधुबाला

सुब्रह्मण्यम स्वामी

'भारत में श्रीलंका का विलय ही अब एक मात्र रास्ता है'

क्या श्रीलंका भारत के लिए वियतनाम सिद्ध होगा? यह एक भयावह संभावना है और भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन के दौरान श्रीलंका में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लगता है कि हमारे पांव वहां बुरी तरह फंस चुके हैं। हां, यह हो सकता है कि भारत सरकार या राजनीतिक नेतृत्व के लिए इसका अंजाम इतना बुरा न हो जितना अमरीकी राष्ट्रपति को अपनी वियतनाम नीति के कारण भुगतना पड़ा था। श्रीलंका के साथ समझौता करते समय जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, वे अब सही लगने लगी हैं।

श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों ने विरोध किया था, परंतु राजनीतिक निर्णय को बहाल रखा गया। अब स्थिति यह है कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका की ओर से हमारी सेना युद्ध कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक ३० सैनिक हलाक हो चुके हैं। आगे कितनी जानें जायेंगी, कहा नहीं जा सकता। क्या इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तमिलनाडु में हमारी इस नीति के विरुद्ध काफी आक्रोश है और इस बात पर गहरा असंतोष है कि तमिल उग्रवादी हमारी ही सेना की गोलियों के शिकार हो रहे हैं। अन्नाद्रमुक को खासतौर से इस बाद की चिंता है कि द्रमुक वर्तमान स्थिति से राजनीतिक लाभ उठा सकती है।

क्या लिट्टे उग्रवादियों को काबू में लाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति जयवर्द्धने सिंहली उग्रवादियों के हिंसक दबाव का सामना कर पायेंगे? श्रीलंका में भारतीय सेना भेजे जाने के निर्णय से इस प्रकार की शंकाएं बढ़ती जा रही हैं।

'माया' प्रतिनिधि पद्मा शास्त्री ने श्रीलंका समस्या पर सुब्रह्मण्यम स्वामी से बातचीत की उसी के आधार पर प्रस्तुत हैं श्रीलंका समस्या पर सुब्रह्मण्यम स्वामी के विचार:

श्रीलंका समस्या की शुरुआत बिलकुल अभी नहीं हुई है। वास्तव में, इस समस्या की जड़ें १९४८ में हुई घटनाओं से जुड़ी हैं। उस वर्ष, श्रीलंका को भारत से अलग करके स्वतंत्र कर दिया गया। यद्यपि ऐसी कोई मांग श्रीलंका में नहीं उठायी गयी थी और न ही स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी कांग्रेस के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव था। यह ब्रिटिश सरकार का एकतरफा फैसला था। दुखद बात यह रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने भी, जो उस समय उत्तरी भारतीयों के हाथ में था, इस विभाजन की कोई चिंता नहीं की। इससे भी दुखद बात यह सिद्ध हुई कि दक्षिण के नेताओं ने, विशेषकर तमिलों ने, इस विभाजन के विरुद्ध किसी प्रकार का राजनीतिक शोर नहीं मचाया। उन्हें उस समय श्रीलंका को भारत से अलग किये जाने के निर्णय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए थी।

श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों के हाथ में निर्विरोध सत्ता आ गयी। स्वतंत्रता मिलते ही उन्होंने तमिलों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहां तक सिंहलियों का प्रश्न है, वे कभी भारत के विरुद्ध नहीं थे। वे आज भी अपने को बिहार और उड़ीसावासियों का वंशज बताते हैं, लेकिन तमिलों के प्रति उनके मन में ईर्ष्या थी। इसका कारण तमिलों का अधिक शिक्षित और समृद्ध होना था। सिंहलियों को लगा कि अगर उन्हें किसी से खतरा है तो वह तमिलों से। विशेषकर, बुद्ध अनुयायियों को तो यह भय था कि आगे चलकर हिंदू तमिल भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा संचालित आंदोलन के माध्यम से श्रीलंका में अपना धार्मिक सिक्का जमा लेंगे। उन्हें यह आशका थी कि श्रीलंका एक दिन हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अतः सिंहलियों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि श्रीलंका जैसे बहु-संप्रदाय राष्ट्र में उपयुक्त 'संघात्मक' संविधान के बजाय 'एकात्मक' संविधान ही लागू हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तुरंत एक नागरिकता अधिनियम पारित किया जिसमें यह मनमानी व्यवस्था की गयी कि ऐसे ही तमिल श्रीलंका के नागरिक माने जायेंगे, जो ४८ घंटों में इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करें कि उनके पिता व दादा श्रीलंका में पैदा हुए थे। स्पष्ट है कि ४८ घंटों के अल्प समय में ऐसा प्रमाणित करना सभी तमिलों के लिए असंभव था। इस संबंध में भारत की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी। फलस्वरूप, श्रीलंका के अनेक तमिल 'राज्यहीन' घोषित कर दिये गये, यद्यपि वे सब वहीं जन्मे थे।

इसके विपरीत भारतीय नागरिकता कानून में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है, वह भारतीय नागरिक बन जायेगा, चाहे उसका पिता भारतीय हो या नहीं। इसके विपरीत, श्रीलंका में यह व्यवस्था की गयी कि कोई भी तमिल जिसके दादा श्रीलंका में पैदा नहीं हुए थे, वहां का नागरिक नहीं होगा। इस प्रकार श्रीलंका में नागरिकता के लिए निर्धारण तिथि (कट-ऑफ-डेट) १८५० रखा गया। असम में जब ऐसी ही समस्या पैदा हुई तो भारत ने १९७१ को 'कट-आफ' तिथि निर्धारित की, जबकि १९३५ या १९३७ को 'कट-ऑफ' तिथि चुनने के बजाय श्रीलंका ने १९४८ में १८५० को 'कट आफ' तिथि माना, और इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में तमिलों को नागरिकता से वंचित रखा। इससे बड़ी एक मूर्खता यह और हुई कि पंडित नेहरू ने इसे मान लिया और बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे,

सुब्रह्मण्यम स्वामी

> *"हमें ब्रिटिश सरकार के १९४८ के कृत्य को उलट देना चाहिए और श्रीलंका को भारत का अंग बना लेना चाहिए...यदि हम ऐसा नहीं करते, तो भावी घटनाओं का इस देश की एकता पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा।"*

हमारी सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिया, जिसके अनुसार ऐसे सभी 'राज्यहीन' तमिलों को भारत में आने की छूट दे दी गयी, जैसे कि उन सब के लिए भारत ही जिम्मेदार था। इस तरह एक गलत धारणा ने जन्म लिया कि श्रीलका के लिए तमिल 'विदेशी' हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वहां के लिए विदेशी तमिल नहीं सिहली हैं। सिहली श्रीलंका में बिहार या उड़ीसा से गये, जबकि तमिल वहां पर शुरू से ही रह रहे हैं। मजबूर होकर, श्रीलंका के तमिलों ने भारत द्वारा उनके प्रति की गयी नजरअंदाजी को बुझे मन से स्वीकारा और हीन भावना से ग्रस्त सिहलियों के साथ वहीं पर कार्यरत हो गये। केवल उन्होंने यह मांग उठायी की श्रीलंका के लिए संघात्मक संविधान और दो राज्यों—एक तमिल और एक सिहली—की व्यवस्था की जाये। इन दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग विधानसभा तथा केंद्र में संसद की मांग भी उठायी गयी। परंतु सिहलियों ने इस मांगों को ठुकरा दिया और वे इस बात पर डटे रहे कि देश भर के लिए केवल एक ही संसद रहेगा। फलस्वरूप, चुनाव में ५१ प्रतिशत मत पा लेने वाला दल सत्ता का हमेशा अधिकारी बना रहेगा। इस तरह, सिहली ने अपनी राजनीतिक प्रभुता बना ली—प्रशासन में और समाज में भी।

परंतु इसके बावजूद भी सिहली अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस न कर सके। अपनी प्रभुता को बनाये रखने के लिए उन्होंने अनेक अन्य कानून बनाये। जैसे, यह व्यवस्था की गयी कि एक तमिल विश्वविद्यालय में तभी प्रवेश पा सकेगा, जब उसे सिहली से २५ प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हों। इस प्रकार उच्च शिक्षा व नौकरी के लिए तमिलों को मिलने वाले अवसर सीमित कर दिये गये। इस पर भी, भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखायी और श्रीलंका से तमिल उच्च शिक्षा के लिए भारत आकर समृद्धि की ओर गतिमान होने लगे। श्रीलंका में १९७७ में दंगों की शुरुआत हुई। १९८१ और १९८३ में दंगे फिर हुए—और उसके बाद हुई मार-काट में हजारों तमिलों की जानें गयीं।

समस्या अब यह है कि तमिलों और सिहलियों का एक साथ मिलकर रहना असंभव हो गया है—क्योंकि सिहली तमिलों के निर्मम हत्यारे के रूप में खुल कर सामने आ चुके हैं। प्रश्न यह है कि अब क्या करना चाहिए? इसके लिए संसद में दो सुझाव मैंने पहले ही दे रखे हैं—वास्तव में, श्रीलंका में भारतीय सेना भेजे जाने की बात सर्वप्रथम मैंने ही कही थी। मानवसंहार पर १९४८ में यू०एन० जनरल असेम्बली द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में हम श्रीलंका की अनुमति के बिना ही वहां सेना भेजने के हकदार थे। १९४८ के इस प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी देश पड़ोसी देश में हो रहे नरसंहार को दवाने के लिए वहां अपनी सेना भेज सकता है। श्रीलंका में निःसंदेह नरसंहार हो रहा था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस बात की पुष्टि की थी और विदेश मंत्री के रूप में बलीराम भगत ने संसद में ऐसा बयान भी दिया था।

दूसरी बात यह है कि श्रीलंका में एक बार प्रवेश करने के बाद श्रीलंका को 'एक देश के रूप में छोड़कर भारतीय सेना वहां से वापस नहीं आ सकती। वहां तमिल क्षेत्र बहुत छोटे हैं, बिना विदेशी सहायता के उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रह सकती। यदि भारत ने तमिल ईलम की सहायता बाहर रहकर ही की होती तो मुकाबले के लिए सिहली क्षेत्र किसी बड़ी महाशक्ति की सैन्य सहायता अवश्व लेते और इस तरह भारत से केवल ३५ किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र भीषण युद्धस्थल बन जाता। अतः मेरा सुझाव यह है कि हमें १९४८ में ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये फैसले को उलट देना चाहिए और श्रीलंका को भारत का अंग बना लेना चाहिए। श्रीलंका को दो भागों में विभक्त करना होगा, एक सिहली और एक तमिल। इन दो भागों में भारतीय राज्यपाल भेजना होगा—एक पंजाबी राज्यपाल तमिल प्रांत में और किसी मराठी या गुजराती को सिहली प्रांत में। हमने सिक्किम में भी ऐसा ही किया था।

प्रश्न यह है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी? वह इस पर निर्भर करेगा कि हम स्थिति को कैसे संभालेंगे। पहले ही मेरा यह विचार था कि यदि हमारी सेना श्रीलंका में जाती है तो अमरीका या रूस या अन्य कोई देश कुछ नहीं कर सकता है। श्रीलंका का क्षेत्र भारत के काफी नजदीक है और इसलिए किसी अन्य देश के लिए दखल देना सभव नहीं है। मैंने जो कहा था वह अब साबित हो गया है, हालांकि भारतीय सेना श्रीलंका में सामने से न जाकर समझौते का सहारा लेकर पिछले द्वार से वहां गयी है। ऐसे लोगों को जो कानून प्रिय हैं उन्हें यह रास्ता ही पसंद है, परंतु, मेरा खयाल है कि हमें कानूनी रास्ते से ही नहीं चलना चाहिए। हमें तो यह देखना है कि कौन सा कदम प्रभावशाली है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी

> *"यदि श्रीलंका से अब भारतीय सेना बुला ली जाती है, तो वहां सिंहली तमिलों को गाजर-मूली की तरह काट डालेंगे। इस तरह तमिलनाडु में एक बार फिर यह भावना जन्म लेगी कि उत्तर भारतीय नेतृत्व ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया है।"*

मेरा सुझाव है कि अब श्रीलंका को भारत में मिला देना चाहिए और सभी उग्रवादियों को जेल में डाल देना चाहिए। सिहलियों और तमिलों में जो सूझबूझ वाले राजनीतिक तत्व हैं, उन्हें बढ़ावा देना होगा। जयवर्द्धने को भारत के किसी बड़े राज्य—उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश—का राज्यपाल का पदभार संभालने के लिए आमंत्रित करना चाहिए जिससे कि प्रशासन के लिए उन्हें श्रीलंका से भी बड़ा क्षेत्र मिल सके और इस तरह श्रीलंका में शांति स्वतः लौट आयेगी। ब्रिटिश सरकार ने १९४७ के उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत एक संयुक्त भारत तो बनाया, परंतु साथ में अनेक छोटे-छोटे राज्यों को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने ऐसे सभी छोटे राज्यों को भारत में मिलाने का सराहनीय कार्य किया। ब्रिटिश गणित के अनुसार श्रीलंका में भी दो तमिल राज्य बनते थे और उन्हें भी स्वतंत्र घोषित करना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसे विश्वास था कि आगे चल कर उन्हें भारत आने का न्यौता यहीं के लोगों से फिर मिलेगा और उस स्थिति में श्रीलंका उनके लिए एक महत्वपूर्ण अड्डे के रूप में काम आयेगा।

यदि मैं सिहली होता तो निःसंदेह अपने ही देश को बेच देने के लिए जयवर्द्धने की निंदा करता। शुरू में तो उन्होंने भारत की तीव्र आलोचना की और फिर अपनी जान बचाने के लिए भारत की ही मदद मांगी। परंतु, अब स्थिति यह है कि यदि हम श्रीलंका को भारत में मिलाने की कार्रवाई नहीं करते, तो आगे होने वाली घटनाओं का इस देश की एकता पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सेनाओं को अपनी लड़ाई तमिल उग्रवादियों के विरूद्ध जारी रखनी पड़ेगी और इस तरह निर्दोष तमिल भी उनके हाथों मारे जायेंगे। इससे श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु में भी भीषण आक्रोश पैदा होगा। और यदि श्रीलंका से अब भारतीय सेनाएं वापस बुला ली जाती हैं तो वहां सिहली तमिलों को गाजर-मूली की तरह काट डालेंगे और इस तरह तमिलनाडु में एक बार फिर यह भावना जन्म लेगी कि उत्तर भारतीय नेतृत्व ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया है और इसलिए तमिलनाडु को भारत से आजादी मिलनी चाहिए। यह एक भयावह स्थिति होगी और ऐसी सम्भावनाओं से हम अपनी आंखें मूंद नहीं सकते।

अतः भारत की सुरक्षा के लिए श्रीलंका में दूरगामी शांति बनाये रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यही एक रास्ता बचता है कि भारत में श्रीलंका का विलय हो और तदुपरांत वहां के सिहली और तमिल मिलजुल कर रहें। ■

वी०पी० सिंह की यात्रा

सत्तारूढ़ दल में हड़कम्प

अभूतपूर्व स्वागत: रायपुर में वी०पी० सिंह, विद्याचरण शुक्ल और अरुण नेहरू

मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान भूतपूर्व रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के स्वागत में जुटी अभूतपूर्व भीड़ क्या उनकी भ्रष्टाचार विरोधी मुहीम का समर्थन करने के लिए जुटी थी या वह कांग्रेस-इ के इन बागी नेताओं और फिल्मी सितारे राज बब्बर को देखने के लिए एकत्र हुई थी? वी०पी० सिंह की इस यात्रा ने प्रदेश के कांग्रेस-इ खेमे में कैसी हलचल मचा दी है?

राजा मांडा का मध्यप्रदेश से कभी कोई सीधा संबंध या सरोकार नहीं रहा, लेकिन पिछले दिनों वह मध्यप्रदेश में जहां-जहां भी गये लोगों ने पलक पांवड़े बिछाकर उनका स्वागत किया, उन्हें सुना और सरांहा। सत्तारूढ़ दल के नेताओं को यह उम्मीद कतई नहीं थी कि इंका से निष्कासित वी०पी० सिंह के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। सत्तारूढ़ नेताओं की इस धारणा का कारण यह था कि मध्यप्रदेश में किसी भी विधायक, सांसद या प्रभावी नेता ने वी०पी० सिंह और उनकी असंतुष्ट बिरादरी की हिमायत में आगे आने का साहस नहीं दिखाया था। ऐसे में, श्री सिंह को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ के उमड़ने से इंका नेताओं का बदहवास होना स्वाभाविक था। यह इसी बदहवासी का नतीजा था कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए जब भीड़ के आंकड़ों को झुठलाना संभव नहीं हुआ तो संगठन के मुखिया सांसद दिग्विजय सिंह ने राजा मांडा के मेजबान सांसद विद्याचर[illegible]ुक्ल की संपत्ति की जांच की मांग कर डाली और सत्ता प्रमुख मोतीलाल वोरा ने कहा कि भीड़ तो 'पंच सवारों' को बस देखने के लिए आती है।

पंच सवार: मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का पंच सवारों से तात्पर्य विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, विद्याचरण शुक्ल और रामधन से था, लेकिन एक और यानी छठे सवार की गिनती करना तो श्री वोरा भूल गये। यह छठा सवार और कोई नहीं फिल्मी अभिनेता राज बब्बर था, जिसकी मौजूदगी से राजा मांडा की सभाओं में न केवल 'ग्लैमर' का संचार हुआ, वरन रायपुर में लक्षाधिक लोगों की सभा में उसने जमकर वाह-वाही भी लूटी। 'वी' फार विश्वनाथ, 'वी' फार विद्याचरण और 'वी' फार विक्ट्री का नारा देते हुए राज बब्बर ने जनसमूह से कहा कि इंसाफ का तराजू अब आपके हाथ में है और आपको ही अंतिम फैसला करना है। उन्नीस सितंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह डेढ़ दिन के लिए मध्यप्रदेश आये। हलचल और हंगामा पैदा करने के लिए डेढ़ दिन का समय ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनके डेढ़ दिन के दौरे ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं की नींद हराम कर दी। पार्टी के छोटे-बड़े नेताओं में हड़बोंग मचने का कारण यह था कि रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में राजा मांडा और उनके साथियों का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। २० सितंबर को भोपाल में हवाई अड्डे पर 'माया' से चर्चा में आरिफ व राज

बब्बर ने रायपुर के कार्यक्रम को शानदार बताते हुए कहा कि रायपुर में उनके नेता और उन लोगों का जैसा स्वागत हुआ, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ।

ऐतिहासिक सभा: शुक्ल के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वह राजनीतिक दृष्टि से खंदक की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने गहरे और व्यापक राजनीतिक अनुभव के आधार पर वह यह बात बखूबी जानते हैं कि इसमें थोड़ी भी चूक या ढिलाई उनके पांवों तले से जमीन सरका सकती है। मध्यप्रदेश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में अपने जनाधार को पुष्ट करने के प्रयोजन से ही उन्होंने मध्यप्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरे के श्रीगणेश के लिए अपने गृहनगर रायपुर को चुना और कार्यक्रम की सफलता के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कीं। कहना न होगा कि विद्या भैया अपने प्रयोजन में सफल रहे और रायपुर में सप्रे शाला में हुई महती सभा ने १९७७ में हुई विजयलक्ष्मी पंडित और उसके बाद हुई बाबू जगजीवनराम की ऐतिहासिक सभाओं की याद ताजा कर दी।

विद्या भैया की जयकार: रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में कार्यक्रम की अपार सफलता से विद्याचरण का परम प्रसन्न होना स्वाभाविक था। स्वागत से उत्फुल्ल वी०पी० सिंह ने रायपुर में आम सभा में विद्या भैया की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि यह धरती और यहां के लोगों का उत्साह देख कर हमें यह अंदाज हो गया कि विद्या भैया के लिए लोगों के मन में कितना प्रेम और लगाव है। उन्होंने कहा कि विद्या भैया ने तो लड़ाई शायद हमसे बहुत पहले से शुरू कर दी थी। दुर्ग में श्री सिंह की सभा माकपा नेता कामरेड पी०के० मोइत्रा की अध्यक्षता में हुई और यहां असंतुष्टों की सफलता यह रही कि राघवेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में करीब डेढ़ हजार इंका कार्यकर्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद में शरीक हो गये। विद्याचरण शुक्ल की मेजबानी में विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यक्रमों की सफलता से दो नतीजे एक साथ निकले। एक ओर तो श्यामाचरण शुक्ल के इंका में प्रवेश का मामला एक बार फिर जोर-शोर से उछला, दूसरी ओर सत्ता शिविर से विद्याचरण शुक्ल की संपत्ति की जांच की मांग उठने लगी। वी०पी० सिंह के कार्यक्रम के बहाने बहुत दिनों से चुप्पी साधे और कांग्रेस की देहरी पर बरसों से अटके श्यामाचरण शुक्ल को भी बोलने का मौका मिल गया। वी०पी० सिंह के छत्तीसगढ़ दौरे के दो दिन पूर्व दिल्ली में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वी०पी० सिंह ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने नेता के साथ विश्वासघात किया और नेता व पार्टी को क्षति पहुंचायी। उन्होंने कहा कि वी०पी० सिंह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। श्यामाचरण के इस बयान से यह समझा जा रहा है कि एक तो उनके इंका में प्रवेश का रास्ता प्रशस्त हो गया है, दूसरे उन्होंने यह वक्तव्य आलाकमान को प्रसन्न और अनुकूल करने के मकसद से दिया है। कमलापति त्रिपाठी के इस आशय के बयान से भी श्यामाचरण के प्रवेश की अटकलों को हवा मिली है कि पुराने कांग्रेसजनों को पार्टी में लिया जाना चाहिए। जहां तक प्रादेशिक नेताओं का प्रश्न है, अधिकांश का कहना है कि इस बारे में फैसला आलाकमान को करना है और वह सबको शिरोधार्य होगा, लेकिन दिलचस्प यह है कि रायपुर के दो नेताओं ने परस्पर विरोधी बयान जारी किए। रायपुर के प्रभारी एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री डा० कन्हैयालाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल को प्रवेश देने से राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी तो विधायक लक्ष्मी नारायण इंदूरिया ने कहा कि श्यामाचरण के प्रवेश से दल कमजोर होगा और विद्याचरण शुक्ल मजबूत होंगे। जाहिर है कि प्रवेश के मामले पर प्रदेश के नेता दो सर्वथा विपरीत खेमों में बंटे हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें प्रवेश मिलता है, तो तय है कि, आलाकमान उनका उपयोग असंतुष्ट नेताओं के जमावड़े, विशेषतौर पर विद्याचरण शुक्ल की काट के तौर पर करना चाहेगा।

इन्हीं दिनों सत्तारूढ़ दल की ओर से विद्याचरण शुक्ल की संपत्ति की जांच की मांग उठने

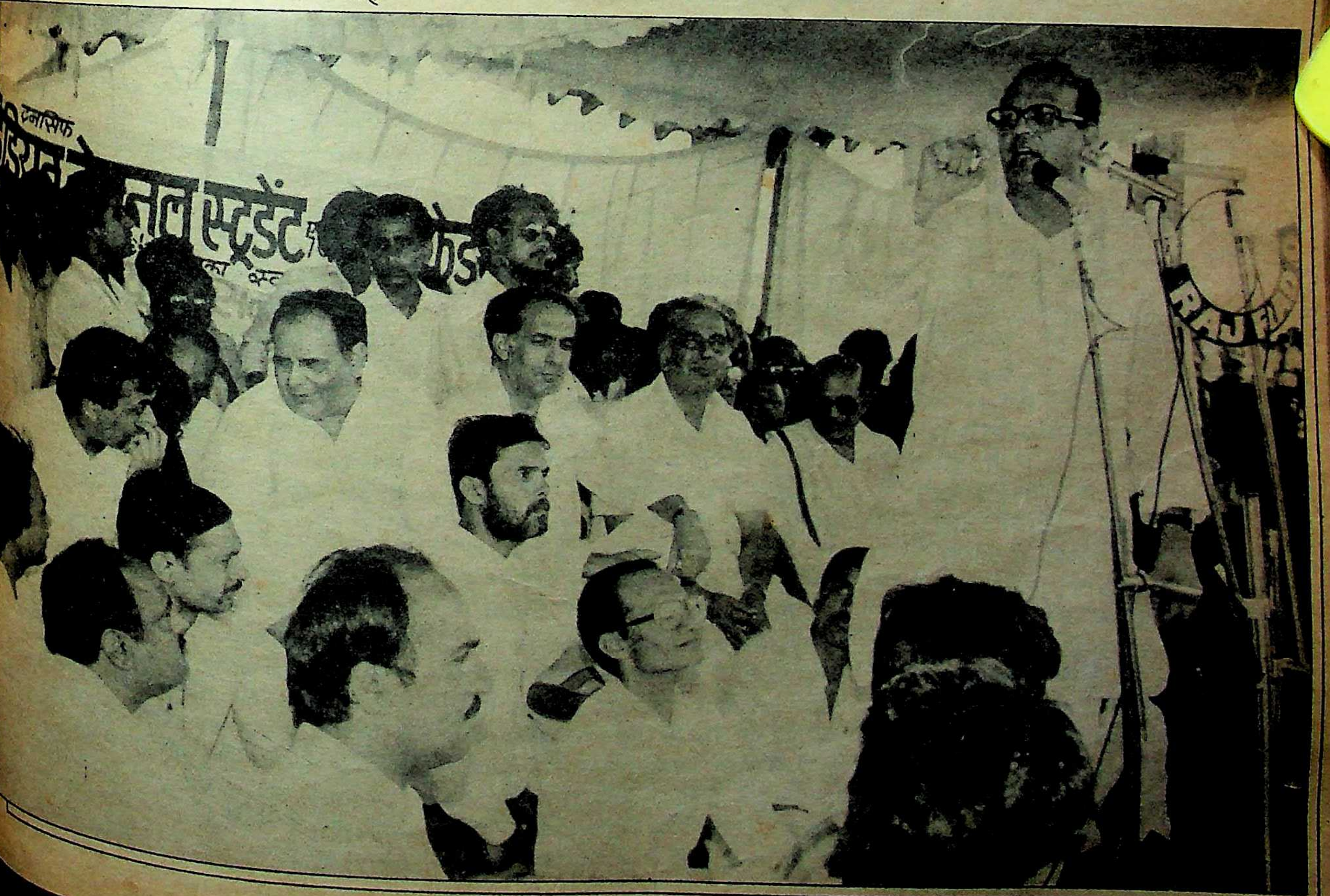

वही रटारटाया भाषण: भोपाल में वी०पी० सिंह

लगी। मांग करने में अग्रणी रहे मध्यप्रदेश कांग्रेस-इ के अध्यक्ष व सांसद दिग्विजय सिंह तथा रायपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसद केयूरभूषण। केयूरभूषण ने रायपुर में जारी एक वक्तव्य में कहा कि विद्याचरण शुक्ल की उस अनापशनाप संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने विगत करीब दो दशकों में पद का दुरुपयोग करके कमाई है। इन्हीं दिनों यह खबर भी उड़ी कि राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को श्री शुक्ल की संपत्ति की जांच का दायित्व सौंपा है। प्रशंसकों और समर्थकों में राजा साहब के नाम से चर्चित व संबोधित दिग्विजय सिंह ने इस तरह की जांच का स्वागत किया और श्री शुक्ल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए उसकी जांच की मांग की। श्री शुक्ल के खेमे में इसकी तीखी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। श्री शुक्ल के प्रवक्ता बेनी माधव तिवारी ने कहा कि विद्या भैया ने अपनी आय व संपत्ति का ब्यौरा कभी नहीं छिपाया। श्री तिवारी ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने विद्याचरण के कांग्रेस में रहते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग क्यों नहीं की। क्या कांग्रेस से निकलते ही आदमी बेईमान हो जाता है और कांग्रेस में रहने से पाक साफ? आरोपों की अदलाबदली का प्रसंग यहीं समाप्त नहीं हुआ। सांसद-द्वय द्वारा मांग की खबर जब श्री शुक्ल तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि वह अपनी संपत्ति की जांच कराने को तैयार हैं, लेकिन सरकार दिग्विजय

फिल्मी ग्लैमर का लाभ: राज बब्बर भोपाल की एक सभा में

वी०पी० और वी०सी०:

क्या कहते हैं लोगबाग?

समकालीन राजनीति में विश्वनाथ प्रताप सिंह की भूमिका और उनकी अगुवाई में वी०सी० शुक्ल के अभियान के बारे में 'माया' ने जब लोगों से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क साधा तो अनेक रोचक व उल्लेखनीय बातें सुनने को मिलीं। वी०पी० सिंह पर सबसे रोचक टिप्पणी की मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने। श्री वोरा ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वासघात प्रताप सिंह हैं और इतिहास उन्हें इसी रूप में याद करेगा। केंद्रीय संचार मंत्री अर्जुनसिंह ने कहा कि वी०पी० सिंह मध्यप्रदेश में इंका के खिलाफ राजनीतिक आधार बनाने में सफल नहीं होंगे। यह पूछने पर कि क्या वी०पी० के दौरे से वी०सी० को ताकत मिलेगी, श्री सिंह ने कहा, "जब स्वयं का प्रभाव नहीं है, तो उधार के प्रभाव से उन्हें क्या लाभ होगा?

अ०भा०अनुसूचित जाति परिषद के प्रांतीय महामंत्री रमेश दामले ने कहा कि वी०पी० अपने अभियान में पचास प्रतिशत सफल रहे हैं। बड़ी बात यह कि राजीव गांधी की 'मिस्टर क्लीन' की छवि धूमिल हुई है।

मध्यप्रदेश में भी इंकाजनों के मन में शंका-संदेह पैदा हो गया है और बड़ी संख्या में इंकाजनों का चुनाव के पूर्व पलायन हो सकता है। प्रदेश इंका के संयुक्तमंत्री किशन पंत की दलील औरों से सर्वथा अलग है। श्री पंत का कहना है कि विद्याचरण मध्यप्रदेश में कभी भी 'फोर्स' नहीं रहे। जो लोग उनके अग्रज श्यामाचरण शुक्ल के साथ थे या तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरोधी थे, वे समय व परिस्थितियों के कारण वी०सी० के इर्द-गिर्द जरूर एकत्र हो गये थे। वी०सी० के विपरीत श्यामाचरण जरूर प्रदेश में फोर्स रहे और उनका आज भी असर है। पेशे से चिकित्सक व भोपाल के अभिजात्य वर्ग में खासे लोकप्रिय डा० प्रशांत तिवारी ने कहा— "जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या की, उसी प्रकार वी०पी० जैसे राजनीतिक अंगरक्षकों ने राजीव की राजनीतिक हत्या की चेष्टा की। दरअसल, राजा व सामंतगण एक व्यापक षड्यंत्र का जाल बुन रहे हैं, जबकि दहिया ट्रस्ट व चुरहट ट्रस्ट से सामंतों के भ्रष्टाचार की कलई खुल चुकी है। वी०पी० ने राजीव की कीमत पर अपनी छवि को चमकाना चाहा। वह जे०पी० बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं सकेंगे।

हरिजन नेता एवं लोक निर्माण मंत्री दुर्गादास सूर्यवंशी की मान्यता है कि लोग वी०पी० को देखने जाते हैं कि चलो देख आयें कैसा है, क्या कहता है? इसका मतलब यह नहीं कि लोगबाग उसके साथ हैं। श्रमिक नेता शिवकुमार उरमलिया मानते हैं कि वी०पी० की सभाओं में इसलिए भीड़ जुटती है क्योंकि वह विवादास्पद हैं। वह बुनियादी सवालों को उठाने में विफल रहे हैं। खुद वी०पी० की छवि उज्ज्वल नहीं है और उनके प्रति आकर्षण अस्थायी है। नाम न छापने के आग्रह पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के इंका के एक विधायक ने कहा कि वी०पी०वी०सी० एंड कंपनी खुद जीते या न जीते, लेकिन चुनाव में वोटों में सेंध लगाकर इंका का भट्ठा जरूर बैठा देगी। 'विश्वनाथ प्रताप सिंह संगठन' की स्थापना कर उसे कुछ माह बाद भंग करने का काम कर चुके विजयदास की मान्यता है कि वी०पी०सिंह की हवा ज्यादा दिन चलेगी नहीं और अंतिम लड़ाई इंका ही जीतेगी। सब्जी विक्रेता रामलाल ने कहा— "वी०पी० सिंह काहे के राजा। गली-गली फकीर जैसे घूम रहे हैं। उनसे ज्यादा दौलत तो मंत्रियों के पास है।" स्वायत्त शासन मंत्री और वोरा मंत्रिमंडल के एकमात्र सिख सदस्य तनवंतसिंह कीर की नजरों में वी०पी० सिंह और उनके साथी 'आस्तीन के सांप' हैं और उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि वे इस्तीफा देकर जनता का सामना करें।

—सुधीर सक्सेना

काले झण्डे: वी०पी० सिंह के विरोध में कांग्रेस-इ का प्रदर्शन

सिंह की मांग पर कार्रवाई करने को तत्पर प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में मेरा प्रस्ताव है कि श्री सिंह मेरे साथ अपनी संपत्ति की अदलाबदली कर लें। श्री शुक्ल ने चुटकी लेते हुए कहा कि निश्चय ही श्री सिंह मेरे इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देंगे, क्योंकि मेरा यह प्रस्ताव उन्हें बहुत मंहगा पड़ेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि जनता काल में भी उनकी संपत्ति की जांच हुई थी किन्तु कुछ हासिल नहीं हुआ। वह अपनी संपत्ति और टैक्सी के ब्यौरे नियमित दाखिल करते आ रहे हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट के बाद उन्होंने संपूर्ण ब्यौरा दल की तत्कालीन नेता को भी सौंपा था। जबलपुर में जब एक पत्रकार ने यह कहा कि आप संपत्ति की अदलाबदली का प्रस्ताव अर्जुनसिंह के समक्ष क्यों नहीं रखते तो श्री शुक्ल ने कहा कि धन के मामले में अर्जुनसिंह की जो हैसियत है, उसके सामने मेरी हैसियत बहुत कम है। आर्थिक अपराध ब्यूरो श्री शुक्ल की संपत्ति की जांच करता है या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है, किंतु फिलहाल ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि इस उपक्रम के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध और परेशान करने की भावना काम कर रही है।

भोपाल में व अन्यत्र वी०पी० सिंह ने साफतौर पर कहा कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन असंतुष्ट कांग्रेसियों के अलावा विपक्षी दलों के नेता उनके इर्द-गिर्द सक्रिय देखे गये। रायपुर में भाजपा व भिलाई में माकपा कार्यकर्ताओं का सहयोग उन्हें मिला। इसी प्रकार भोपाल में जनता पार्टी के यमुना प्रसाद शास्त्री, श्रीमती सविता वाजपेयी, रामानंद सिंह और हृदयमोहन आदि नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस बीच 'माया' को रीवा से खबर मिली कि इन्हीं दिनों वहां पवईदार संघ की बैठक ताला हाउस, रीवा में हुई, जिसमें वी०पी० सिंह को सहयोग व समर्थन देने का फैसला किया गया। इस बैठक में विंध्य के अनेक जागीरदारों व ताल्लुकेदारों ने भाग लिया।

सत्तारूढ़ इंदिरा कांग्रेस के नेता वी०पी० सिंह की सभा में उमड़ी भीड़ को उनकी समर्थक न मानकर तमाशबीनों में गिनते हैं। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने 'माया' से कहा, "मेरी निश्चित धारणा है कि भीड़ का एकत्र होना जनसमर्थन का परिचायक नहीं है। मेरा ख्याल है कि भीड़ राज बब्बर को भी देखने गयी होगी।" अनेक इंका नेताओं ने यह भी शिकायत की कि भीड़ को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है, लेकिन रायपुर में राजा मांडा की सभा में सभाग के पुलिस महानिरीक्षक वेद प्रकाश खन्ना, म०प्र० गुप्तचर विभाग के आई०जी० नरेंद्र प्रसाद, डी०आई०जी० तारन सहित आई०बी० के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से यह नतीजा निकालना गलत नहीं होगा कि शासन को सभा के बारे में स्पष्ट व आधिकारिक जानकारी है। राजनीतिक स्तर पर जायजा लेने के लिए दिग्विजय सिंह और उनके विश्वासपात्र महामंत्री ललित श्रीवास्तव रायपुर के कई फेरे लगा चुके हैं और-तो-और अर्जुन सिंह भी रायपुर हो आये। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने भी २१ सितंबर को रायपुर जाकर अधिकारियों व कार्यकर्ताओं से जानकारी हासिल की। इन नेताओं की भागदौड़ का एक कारण यह भी है कि अक्टूबर-नवंबर में वी०पी० सिंह के इंदौर, उज्जैन व जबलपुर के दौरे पर आने की संभावना है। नवंबर में उन्हें विंध्य के दौरे पर भी लाने के प्रयास चल रहे हैं। श्री वोरा के लिए चिंता का कारण यह है कि बोफोर्स व फेयरफैक्स की बात करनेवाले राजा मांडा ने भोपाल में सूखा व राहत कार्यों के लिए वोरा सरकार को लताड़ा और कहा कि दाल में जो काला है, वह काले धन के काले झंडे दिखाने से दूर नहीं होगा। अमेठी के संजय सिंह, वी०पी० और वी०सी० के मिलन को उ०प्र० और म०प्र० के मिलन की संज्ञा दे चुके हैं, तो रामधन का कहना है कि अगर देश में कोई लहर है तो वह वी०पी० लहर है। जाहिर है कि भविष्य में वोरा सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वी०पी० सिंह मध्यप्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा न कर पायें और मध्यप्रदेश वी०पी० लहर की चपेट में आने से बचा रहे।

छाया: आर०सी० साहू, संजीव गुप्ता

—सुधीर सक्सेना

साक्षात्कार/कमलनाथ सांसद

'अलादीन का चिराग नहीं है राजीव के पास'

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र से सांसद कमलनाथ की लोकप्रियता किसी भी सांसद के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती है। उन्होंने छिंदवाड़ा क्षेत्र को नयी चमकीली शक्ल देने के लिए भरसक कोशिशें की हैं। एक मजेदार बात यह है कि देश के शायद ही किसी सांसद ने अपने मतदाताओं को इतने पत्र लिखे होंगे, जितने सांसद कमलनाथ ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को लिखे हैं। १६८० में कमलनाथ के चुनाव प्रचार के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जब छिंदवाड़ा आयी थीं, तो उन्होंने छिंदवाड़ा के लोगों से कहा था, "वह अपने परिवार का 'तीसरा बेटा' उन्हें सौंप रही हैं।" श्रीमती गांधी का यह तीसरा बेटा बीते सात सालों में बहुत कम मुखर हुआ, लेकिन प्रदेश की राजनीति में उसका गुपचुप मगर महत्वपूर्ण दखल लगातार बना रहा। प्रदेश की गुटीय राजनीति में शक्ति संतुलन की कुंजी बरसों उनके पास रही। बीते सात सालों में कमलनाथ कभी किसी विवाद में नहीं उलझे, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को 'अक्षम मुख्यमंत्री' करार देकर उन्होंने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया, जिसकी अनुगूंज सत्ता के गलियारों में आज भी शेष है। बातचीत की शुरुआत 'एक्सप्रेस' समूह से हुई, जिसके बारे में उनकी दो टूक राय थी कि एक्सप्रेस फिल्मी पत्रिकाओं की सनसनी पैदा करनेवाली पत्रकारिता का निर्वाह कर रहा है। प्रस्तुत हैं, कमलनाथ से हुई बातचीत के महत्वपूर्ण अंश:

माया: क्या आपको यह नहीं लगता कि इधर अनेक कारणों से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लोकप्रियता में गिरावट आयी है?

कमलनाथ: राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गयी थीं। राजीव को प्रधानमंत्री बने करीब तीन साल हो गये हैं। इन तीन सालों में लोगों को यह तो पता चल ही गया है कि राजीव के हाथों में अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन इससे यह अर्थ लगाना गलत होगा कि राजीव की लोकप्रियता में गिरावट आयी है।

माया: रक्षा सौदों में कथित घपलों और दलाली के आरोपों के बारे में आपकी क्या राय है?

कमलनाथ: अभी तक कोई ठोस बात तो सामने आयी नहीं है। हां, विरोधी दलों का प्रचार, हो-हल्ला निरंतर जारी है।

माया: लेकिन इस प्रचार से प्रधानमंत्री की छवि और प्रतिष्ठा पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है?

कमलनाथ: इस प्रचार के बारे में मेरा खयाल है कि राजीव जैसी हस्ती की छवि और प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है। उसे बरगलाया नहीं जा सकता और न ही उसे गलत बातों से मूर्ख बनाया जा सकता है।

माया: लेकिन यदि वी०पी० सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खां जैसे राजीव के नजदीक व सरकार में रहे लोग कुछ कहते हैं तो उसका असर तो होगा ही.....

कमलनाथ: ये लोग तो कांग्रेस से नहीं पदों से निकले हैं और क्या जनता यह नहीं समझती कि पद से निकले व्यक्ति की क्या आवाज होगी? वी०पी० सिंह जगह-जगह मीटिंग कर कह रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आप ही बताइये कि इस प्रचार का क्या उद्देश्य है? और फिर यह कहने का अभिप्राय क्या है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। वह कोई नयी बात तो नहीं कह रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वप्रथम नारा देने—आलमोस्ट आंदोलन छेड़ने का काम राजीव ने ही किया है।

माया: क्या यह बात मायने नहीं रखती कि असंतुष्टों की सभाओं में खासी भीड़ हो रही है?

कमलनाथ: असंतुष्ट नेताओं के भीड़ जमा करने से कोई 'पलटा' (परिवर्तन या फेरबदल) तो होने वाला नहीं। असंतुष्टों की बिरादरी के खास अरुण नेहरू तो आज तक रायबरेली नहीं जा सके हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि अरुण नेहरू वी०पी० सिंह के नेता हैं या वी०पी० सिंह अरुण नेहरू के। असंतुष्टों की जमात अजीब भानुमती का कुनबा है।

माया: सांसद विद्याचरण शुक्ल के इंका से निष्कासन से क्या आपकी दृष्टि में मध्यप्रदेश में इंदिरा कांग्रेस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

कमलनाथ: विद्याचरण के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब उनके बड़े भाई श्यामाचरण शुक्ल के न रहने से, जो प्रांत की राजनीति और शुक्ल परिवार की राजनीति के सूत्रधार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा तो विद्याचरण के इंका में न रहने से भला क्या फर्क पड़ेगा?

माया: पिछले दिनों आपने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को अक्षम मुख्यमंत्री कहा था। ऐसा कहने के क्या कारण थे?

कमलनाथ: मोतीलाल वोरा 'अ-सक्षम' (सक्षम नहीं) प्रशासक हैं, इसमें कोई रिसर्च या इंक्वायरी की जरूरत तो है नहीं।

माया: आपके कथन से यह अर्थ निकाला जा रहा है कि आपने वोरा सरकार को हटाने के लिए अभियान छेड़ दिया है.....

कमलनाथ: मैंने उन्हें हटाने का कोई अभियान या मुहिम नहीं छेड़ी है। मैंने तो जनता की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। मुमकिन है कि उनमें, उनके कामकाज में, प्रशासन में जनता की पीड़ा सुनकर कुछ सुधार आ जाये।

माया: फर्ज कीजिए कि कोई सुधार नहीं आता तो?

कमलनाथ: (हंस कर ठिठोली के मूड में) अगर कोई सुधार नहीं आता तो मैं मोतीलाल वोरा को 'भारत रत्न' (भारत रत्न की उपाधि) देने की अनुशंसा करूंगा।

माया: कुछ लोगों का यह भी खयाल है कि आपने वोरा के खिलाफ बयान देकर अर्जुन सिंह के 'वोरा-हटाओ' अभियान में सहयोग दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाने-अनजाने 'टूल' बन गये हों?

कमलनाथ: अर्जुन सिंह की क्या राजनीति है या क्या गुट है, इसका मुझसे कोई कनेक्शन या संबंध नहीं है। मेरे कथन में गुटीय भावना का समावेश भी कतई नहीं है। मेरा कथन पिछड़े क्षेत्र का विकास न हो पाने के दर्द की अभिव्यक्ति है, पीड़ा का प्रकटीकरण है। मेरे साथ मुझसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता व विधायक हैं और जो मेरे नजदीक हैं, उनका उद्देश्य 'पावर-पालिटिक्स' नहीं है और न ही उनका मकसद सत्ता व तिकड़म की राजनीति करना है।

माया: विरोधी दलों के नेता इन दिनों बारंबार मध्यावधि चुनाव की मांग कर रहे हैं। क्या देश में मध्यावधि चुनाव होने चाहिए?

कमलनाथ: मेरे जिले की जनता ने मुझे पांच साल के लिए चुना है। यह नहीं कि मुझे हर साल प्रमाणपत्र लाना होगा या प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। मैं प्रोबेशन पर तो चुना नहीं गया हूं कि ढाई साल बाद मुझे नियमित किया जायेगा। यह अकेली मेरी या मेरे क्षेत्र की बात नहीं है। यही बात राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है। लगता है कि विपक्षी दलों के मैता ढाई साल के अपने अनुभव को भुला नहीं सके हैं। जैसे ढाई साल में उन्हें चुनाव कराने पड़े, वे चाहते हैं कि कांग्रेस भी कराये। यह मजाक नहीं तो और क्या है?

—सुधीर सक्सेना

के
मुख्यमंत्री
?
(सक्षम
ा
ला जा
टाने के
भियान
की,
क्ति दी
ाज में,
छ
हीं
में)
तीलाल
ी
है कि
र्जुन
योग
जाने-
ति है
शन या
ना का
र्द की
. मेरे
धायक
य
उतका
करना
रहे
पांव
हर
पर तो
ड़ी
ी या
ष्ट्रीय
वपक्षी
को
न्हें
स भी
है ?
सक्सेना

अब बाकी सभी सिंथेटिक इनैमल इसके आगे फीके पड़ जाते हैं

पेश हैं

गारकोट

सुपरग्लॉस

सिंथेटिक इनैमल

अब, गरवारे पेण्ट्स प्रस्तुत करते हैं गारकोट सुपरग्लॉस. एक बिल्कुल ही नया, टिकाऊ और चमकीला सिंथेटिक इनैमल. इसके आगे बाकी सभी इनैमल फीके पड़ जाते हैं.

क्या खूब टिकाऊ.

इसकी एक पतली-सी परत सतह पर फैलकर बरसों उसकी रक्षा करती है. न झुर्रियाँ पड़ें, न छिलके उभरें–मौसम चाहे कितना ही बेरहम क्यों न हो.

क्या खूब चमकीला.

यह सतह को एक ऐसी खूबसूरत चमक देता है जो समय के साथ न तो फीकी पड़ती है, न रंग बदलती है.

ब्रिलियंट व्हाइट, ग्लो व्हाइट और ब्लैक समेत तरह-तरह के ४० आकर्षक रंग-छटाओं में से चुनिए.

दूसरी रंग-छटाएं तैयार करने के लिए गारटिंट यूनिवर्सल स्टेइनर भी मिलता है.

GARCOAT
SYNTHETIC ENAMEL
Garware Paints

GARWARE
गरवारे

गरवारे पेण्ट्स लिमिटेड
एक उत्कृष्ट उत्पादन

GARWARE
गरवारे
Garware Paints
GARCOAT
SUPERGLOSS
SYNTHETIC ENAMEL
GARCOAT
R.K.SWAMY/CPL/3244-HN

इतना टिकाऊ, हमेशा नए का नया. इतना चमकीला, पड़े न कभी फीका.

ये ताज़गी, ये मोहकता...कुदरत के सिवा कहीं और कहां!
Cuticura
Lavender
Mist
A Talc Classique
लैवेन्डर
मिस्ट
एक लाजवाब टैल्क.
झलके इसमें आपका अंदाज़.
Orbit/MP-LM/169 87 H

साक्षात्कार/**मोहसिन खान**

'सब अल्लाहताला की मेहरबानी है'

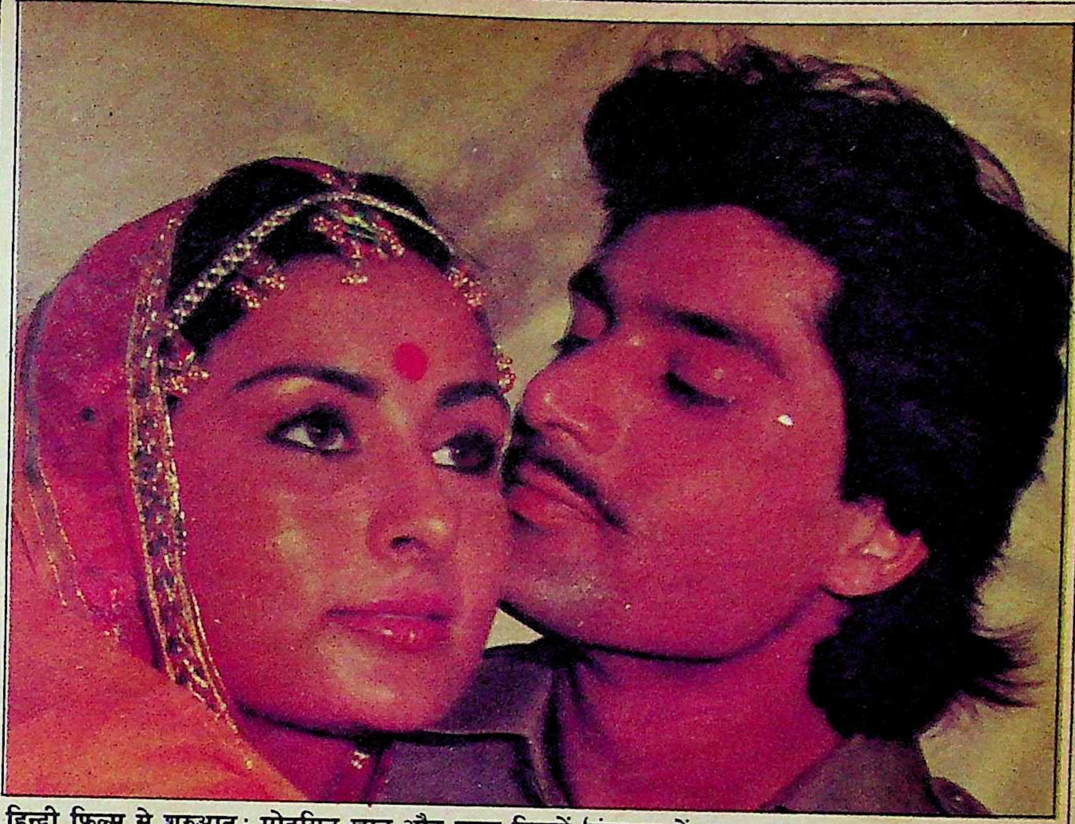

हिन्दी फिल्म से शुरुआत : मोहसिन खान और पूनम ढिल्लों 'बंटवारा में

जयपुर से लगभग ५० कि०मी० दूर सामोद गांव में अलस्सुबह ही भीड़ का तांता लगना शुरू हो गया था। सूर्योदय होते-होते कई हजार की भीड़ सामोद पैलेस के इर्द-गिर्द एकत्र हो चुकी थी। थोड़ी देर में कारों का लंबा काफिला गर्द उड़ाता हुआ सामोद पैलेस के अहाते में दाखिल होना शुरू हुआ, तो भीड़ नारे लगाने लगी और कार से एक-एक कर उतरनेवालों के नाम ले-लेकर चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद भीड़ बेकाबू होने लगती है और पुलिस असहाय-सी दीखने लगती है। पुलिस अफसर की बात अनसुनी कर चुकी भीड़ फिर जोर-शोर से चिल्लाने लगती है, "वी वांट मोहसिन, हमें मोहसिन खान से मिलाइये..."

"अभी तक मोहसिन खान नहीं आये...मेरा विश्वास मानिये। जब वह आ जायेंगे, हम उनसे आपको जरूर मिलवायेंगे...।" पुलिस अफसर बेकाबू हो रही भीड़ को पुनः समझाने की कोशिश करता है, तभी उसके चेहरे पर तेजी से आकर महल के अहाते में रुकती कार को देखकर, चमक आ जाती है। वह तुरंत उस कार से उतर रहे खूबसूरत युवक को लेकर महल के झरोखे में जाता है और नीचे खड़ी भीड़ से मुखातिब होता है— "यह रहे आपके मोहसिन खान!" और भीड़ एकदम से शांत हो जाती है।

"कमाल है, महल के भीतर मौजूद विनोद खन्ना, अमृता सिंह, शम्मी कपूर, पूनम ढिल्लों जैसे सितारों के लिए इतनी चिल्लाहट नहीं हुई, जितनी मोहसिन खान की। अब इसके हिट होने में कोई दो-राय नहीं रही।" इन सितारों के पास बैठा एक व्यक्ति कहता, है तो हर कोई उसकी बात की ताईद करता है और मोहसिन खान के झरोखे से निकल कर भीतर महल में आते ही शम्मी कपूर उसे गले से लगा लेते हैं— "बरखुरदार, आपकी सफलता में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। आप इस फिल्म के रिलीज होते ही स्टार बन जायेंगे। आपने पाकिस्तान के श्रेष्ठतम सलामी बल्लेबाज के रूप में सफलता के झंडे गाड़े हैं, अब फिल्म इंडस्ट्री में भी गाड़ेंगे। इंशा अल्लाह आपकी मदद करेगा..."

यह दृश्य था जयपुर के निकट स्थित सामोद गांव का, जहां फिल्म निर्माता सलीम की, इस वर्ष की सबसे बड़ी स्टारकास्ट फिल्म 'बटवारा' की आउट डोर शूटिंग के लिए सितारों की भीड़ एकत्र हुई थी। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहसिन खान इसी फिल्म से अभिनय की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट सेलेक्शन कमेटी के पक्षपाती रवैये तथा इमरान खान-सरफराज नवाज की आपसी राजनीति का शिकार हो मोहसिन खान को अपने दोस्त जहीर अब्बास की ही तरह जिस अपमानजनक ढंग से सक्रिय क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था और तिरस्कार का घूंट पीना पड़ा उसने उन्हें काफी विचलित किया। अंतःसंघर्ष के इन क्षणों में उनकी बेगम रीना राय ने उनका काफी मनोबल बढ़ाया, लेकिन क्रिकेट का विकल्प तलाशने में मोहसिन को काफी समय लग गया।

अंततः जब उन्होंने इंग्लैंड में खुद का कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बनायी तब उनकी साली बरखा राय ने उनसे अपनी नयी फिल्म में श्रीदेवी के साथ भूमिका निभाने का आफर रखा। लेकिन उनकी पहली फिल्म शुरू हुई 'बटवारा,'। जब मोहसिन के फिल्मों में काम करने, न करने की अटकलें फैली हुई थीं, 'माया' ने सबसे पहले उनके अभिनेता बन जाने की खबर छापी (माया ३१ अगस्त १९८७)। उन्होंने यह साक्षात्कार पहली बार 'माया' को दिया। प्रस्तुत हैं, मोहसिन खान से 'माया' की बातचीत के मुख्य अंश :

माया : क्रिकेट से संन्यास लेकर अचानक फिल्म कलाकार बन जाने की बात कैसे सूझी ?

मोहसिन : जब मैं छोटा था तो उस समय मैंने या किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी बन जाऊंगा और बल्लेबाजी के कई कीर्तिमान मेरे नाम जुड़ जायेंगे। उसी तरह जब मैं क्रिकेट खिलाड़ी बन गया, तो उस समय मेरे दिमाग में फिल्म स्टार बनने की कोई बात नहीं थी। यह सब अल्लाहताला की मेहरबानी है।

माया : आपकी साली (बरखा राय) खुद भी फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने आपको लेकर फिल्म क्यों नहीं बनायी ?

मोहसिन : दरअसल शुरुआत उन्होंने ही की थी। मैंने इंग्लैंड में अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह श्रीदेवी को लेकर फिल्म बना रही हैं। मैं उसमें काम करूं। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उनके जिद करने पर मान गया कि अतिथि भूमिका करूंगा।

वही दूध सी
सफ़ेदी लाए

सारे भारत में सबसे ज़्यादा बिकनेवाली डिटर्जेंट टिकिया

निरमा

१५० ग्राम की ज्यादा बड़ी टिकिया, फिर भी दाम एकदम वाजिबी. दूसरी डिटर्जेंट टिकियाओं की तरह न तो पानी में ज़ल्दी घुलती है, न हाथ में चिपकती है.

तभी तो सबसे ज़्यादा कपड़े धोये. सबसे ज्यादा चले, और आपके कोमल हाथों को कोमल बनाये रखे.

" जगमग सफेदी... जगपसंद
हर गृहिणी की मनपसंद."

निरमा केमिकल वर्क्स, वटवा, अहमदाबाद - ४५.

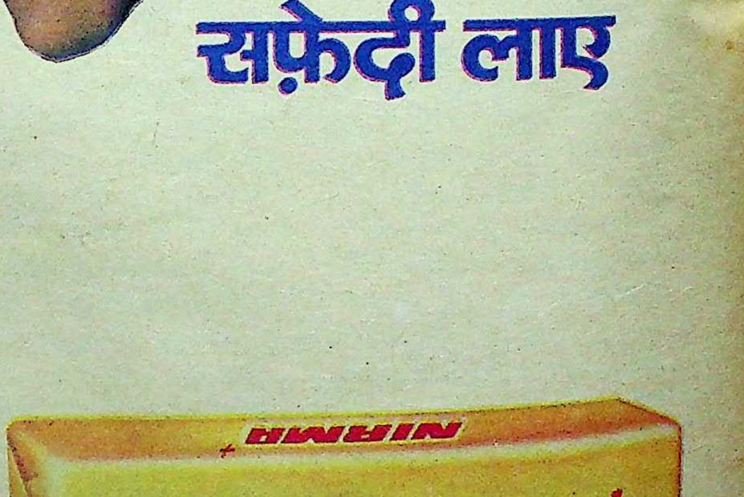
निरमा
निरमा
निरमा
डिटर्जेंट टिकीया

माया : फिर 'बटवारा' का सिलसिला अचानक कैसे शुरू हो गया ?

मोहसिन : अचानक नहीं। रीना और बरखा दोनों चाहती थीं कि इस फिल्म का निर्देशन जे०पी० दत्ता करें। रीना ने एक फिल्म (गुलामी) जे०पी० दत्ता के साथ की थी, और उनसे बहुत प्रभावित थीं। जे०पी० फिल्मों में पहले से ही अत्यधिक व्यस्त थे, अतएव बरखा की फिल्म तुरंत शुरू नहीं कर सकते थे, एक वर्ष लग सकता था। उस समय जे०पी०, सलीम की 'बटवारा' पर काम कर रहे थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना साइन कर चुके थे। एक तीसरे नायक की उन्हें तलाश थी। एक दिन जब उन्होंने मुझसे यह रोल करने के लिए कहा तो मैंने तुरंत 'हां' कर दी।

माया : क्यों ?

मोहसिन : इसके तीन कारण थे। एक तो धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शम्मी कपूर जैसे सितारों के साथ काम करना था—यानी अपनी अभिनय-प्रतिभा को निखारने का पूरा अवसर था। दूसरा जे०पी० दत्ता के साथ काम करने का मौका और तीसरा—यह इस वर्ष की सबसे बड़े बजट की भव्य फिल्म थी। ऐसे मौके सामान्यतया हाथ नहीं आते।

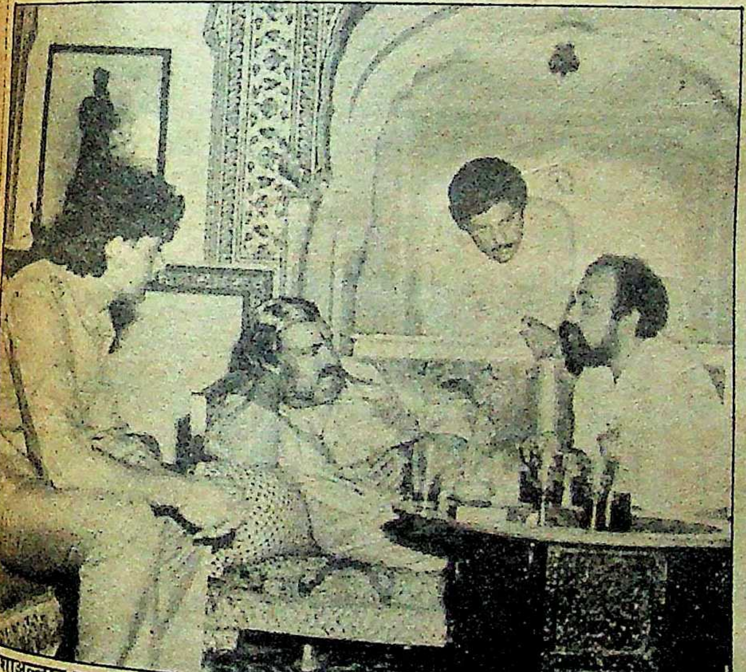
इंशाअल्लाह कामयाबी देंगे : 'बंटवारा' के सेट पर निर्देशक जे०पी० दत्ता और शम्मी कपूर के साथ मोहसिन खान

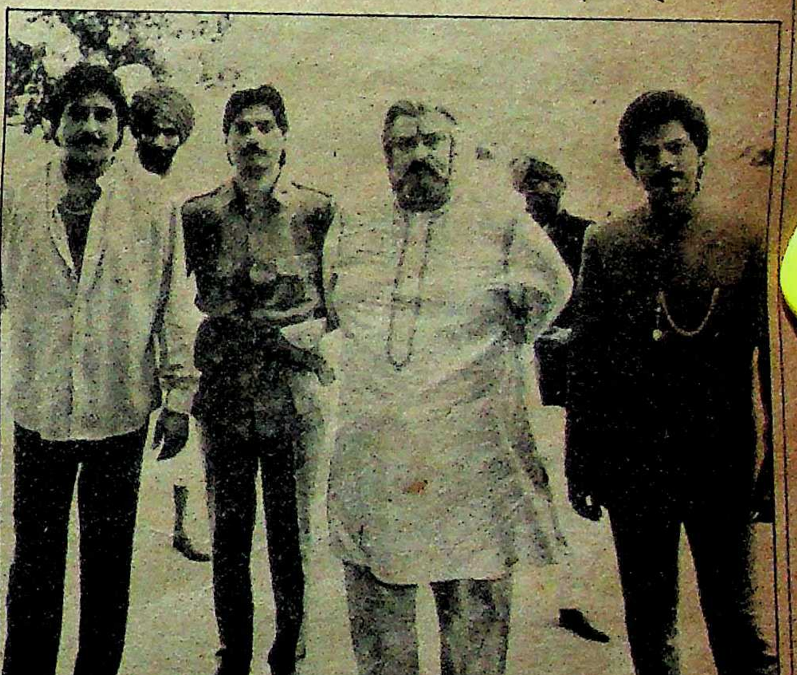
बड़े सितारों के साथ : विनोद खन्ना, मोहसिन खान, शम्मी कपूर, विजयेंद्र घाटगे फिल्म 'बंटवारा' में

माया : लेकिन आपने कुछ और फिल्में भी साइन कर ली थीं और उन्हें छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वे छोटे निर्माताओं की छोटी फिल्में थीं ?

मोहसिन : नहीं, छोटे-बड़े की बात नहीं। जब जे०पी० के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, तभी कई निर्माताओं ने घेरना शुरू किया। इनमें से कुछ परिचित भी थे, इसलिए 'हां' कर दिया। लेकिन 'बटवारा' की शूटिंग पहले शुरू हुई और उन्होंने मेरी ही नहीं, सभी सितारों की 'डेटें' एक साथ ही ले ली थीं, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म को एक वर्ष में खतम कर देना चाहते थे, जबकि दूसरे फिल्मों की न तो शूटिंग ही शुरू हुई थी न ही उन्होंने डेटें ली थीं। इन फिल्म निर्माताओं को मेरे कारण कठिनाई नहीं उठानी पड़े इसलिए मैंने उनसे क्षमा मांग ली। जब अभिनय शुरू ही कर दिया है तो उनकी किसी और फिल्म में काम कर लूंगा।

माया : आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में क्रिकेट के मैदान में सफलता व कीर्तिमानों के झंडे गाड़ने के लिए मशहूर रहे। फिल्म के मैदान में आपकी ओपनिंग कैसी रही ?

मोहसिन : और भी शानदार। पहला ही 'शाट' पहली ही बार में ओ०के० हो गया। सभी ने तालियां बजाकर शाबासी दी। शम्मी कपूर साहब तो इतने खुश हुए कि मुझे गले लगा लिया और बोले, "मोहसिन, हो जाये एक शानदार पार्टी !" शम्मी साहब ने उस रात होटल लौटने पर एक जोरदार पार्टी दी।

माया : पहला शाट क्या था आपका ?

मोहसिन : पहले मैं अपना रोल बतला दूं। पुराने जमींदार-ठाकुर (शम्मी कपूर-आशा पारेख) के तीन बेटों में से एक मैं हूं। दो हैं— विनोद खन्ना एवं विजयेंद्र। इस घराने की तीन बहुएं-अमृता सिंह, पूनम ढिल्लों एवं नीना गुप्ता हैं। दृश्य के अनुसार पुलिस अफसर की ट्रेनिंग लेकर घर लौटते समय रास्ते में एक गिरोह के साथ मुठभेड़ में मैं घायल हो जाता हूं। मेरे स्वागत में खड़े मेरे पिता (शम्मी कपूर) दोनों भाई (विनोद खन्ना एवं विजयेंद्र) तथा गांव के लोगों को मैं अहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैं घायल हूं। पिता के पैर छूकर दोनों भाइयों को गले लगाता हूं और बेहोश होकर गिर पड़ता हूं। यही पहला शाट था मेरा।

माया : क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में फ्लैश लाइटों वाले सैकड़ों कैमरों, टेलीविजन कैमरे को 'फेस' करने के तो आप आदी हो चुके हैं, लेकिन मूवी कैमरे के सामने पेश होते समय नर्वस नहीं हुए आप ?

मोहसिन : कुछ क्षण के लिए तो हुआ था, लेकिन कैमरे के कारण नहीं। १२ अगस्त को सुबह ७ बजे जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो जे० पी० ने कहा कि 'आज तुम्हारा शाट लेंगे, कास्ट्यूम पहन कर तैयार हो जाओ' तो उस समय थोड़ी-सी हिचक हुई थी। कैमरे के सामने मेरे अलावा बड़े-बड़े स्टार थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से सबका शूटिंग करते हुए बड़े बारीकी से अध्ययन किया था। साथ ही सभी छोटे-बड़े कलाकारों के साथ दोस्ताना रवैया हो गया था इसलिए 'कैमरा कांशस' वाली बात नहीं रही।

माया : आपने अभिनय के पहले कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी ?

मोहसिन : ज्यादा कुछ नहीं। हां, प्राइमरी ट्रेनिंग की बरखा ने व्यवस्था कर दी थी, फिर निर्माता सलीम ने घुड़सवारी, फाइटिंग तथा फिल्म से संबंधित दूसरी आवश्यक बातों की तालीम अपने खर्च पर बंबई में ही दिलायी थी।

माया : अगर आपने सरफराज नवाज तथा इमरान खान की आपसी राजनीतिक लड़ाई में सरफराज नवाज का साथ न देकर इमरान का साथ दिया होता तो संभवतः इसी जयपुर में आप रिलायंस वर्ल्ड-कप में पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन होते ?

मोहसिन : अतीत की बातों को कुरेदने से क्या फायदा ? हां, 'बटवारा,' के अगले शिड्यूल की शूटिंग अक्तूबर-नवंबर में जयपुर में होगी, तो शायद वर्ल्ड कप का एक दिवसीय मैच जयपुर में पड़ेगा और खेलनेवाली टीम से मुलाकात होगी।

माया : तब वे एक टेस्ट ओपनर से नहीं फिल्म स्टार से मिल रहे होंगे।

मोहसिन : (हंसते हैं) शायद। फिलहाल तो आप अपने पाठकों से कहिये कि वे मेरे लिए दुआयें मांगें कि अल्लाहताला ने जिस तरह से खेल के मैदान में सफलता नवाजा है, उसी तरह फिल्म के मैदान में भी सफलता दे।

—चित्रा वर्मा

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल

क्या फिर हड़ताल होगी ?

उत्तर प्रदेश के राज्य-कर्मचारियों व शिक्षकों ने १५ सितंबर से ७ अक्तूबर तक शिक्षा संस्थानों व सरकारी कार्यालयों में कामकाज व सूखा राहत कार्य ठपकर अपना न्यूनतम वेतन इतना बढ़वा लिया है कि अब वह केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन से सिर्फ ढाई रुपए कम है- लेकिन सिर्फ ढाई रुपए का अंतर क्यों छोड़ा गया ? गत वर्ष १६ दिनों तक चली हड़ताल के बाद ये अंतर ४६ रुपए था जो इस वर्ष हड़ताल का मुद्दा बना। क्या अब ढाई रुपए की वेतन-वृद्धि को लेकर हड़ताल होगी ? वीर बहादुर सिंह की सरकार और राज्य कर्मचारियों के नेता हड़ताल के मुद्दे क्यों जीवित रखना चाहते हैं ? :

एक वर्ष में दूसरा मौका था, जब प्रदेश के १७ लाख राज्य-कर्मचारी, शिक्षक और राज्य सरकार की आमने-सामने की लड़ाई में कर्मचारियों का पलड़ा भारी रहा। केन्द्र के बराबर वेतन की मांग की लड़ाई इस तरह सफलता की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए दोनों ही पक्षों को काफी खमियाजा भुगतना पड़ा। सरकार के राजस्व कोष पर जहां एक वर्ष में ६२ करोड़ रुपए से ऊपर का अतिरिक्त भार पड़ा है, वहीं कर्मचारी-शिक्षक एकता में भी दरारें पड़ गयी हैं।

प्रदेश में कर्मचारियों के दो बड़े संगठन हैं, राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद और कर्मचारी-शिक्षक महासंघ। कर्मचारी हड़ताल में इन दोनों संगठनों की अपनी अलग-अलग पैंतरेबाजी होती है। समझौते का श्रेय हासिल करने में इन दोनों संगठनों को समय व राजनीति से रिश्ता कायम करना पड़ता है। इन दोनों संगठनों के शीर्षस्थ नेताओं पर दो सत्ताधीशों का वरदहस्त है। राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष बी०एन० सिंह जहां मुख्यमंत्री वीर बहादुर के करीबी हैं, वहीं कर्मचारी-शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष की गणना प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी के बगलगीरों में की जाती है। यही वजह है कि २२ दिन तक खिचनेवाली इस हड़ताल को राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद का कोई सहयोग नहीं मिला। यह अलग बात है कि कर्मचारी संगठन के इस बड़े घटक के असहयोग के बावजूद उपलब्धि हासिल करने का श्रेय कर्मचारी-शिक्षक महासंघ ने हासिल कर लिया।

आक्रोश को बढ़ावा : १५ सितंबर को कर्मचारी-शिक्षकों पर लाठी बरसाते पुलिस और पी०ए०सी० के जवान

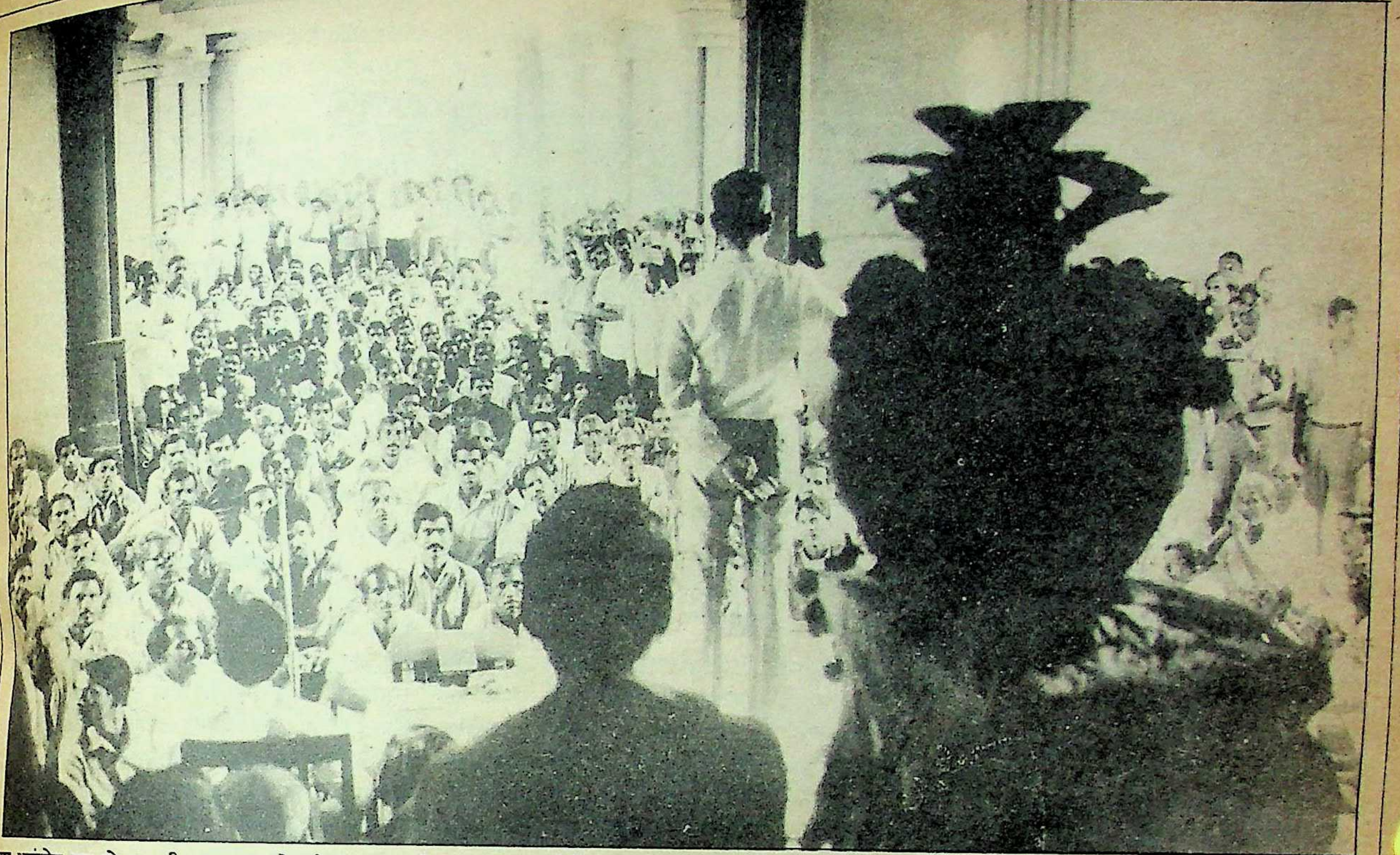

क्या असंतोष दूर हो गया? : हड़ताल के दौरान प्रज्ज्वलित हड़ताल ज्योति

राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने पिछले वर्ष नवम्बर में १६ दिन की हड़ताल की थी। उस हड़ताल का प्रारम्भ भी कर्मचारी-शिक्षक महासंघ ने किया था। ४ दिनों बाद राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने भी विधानभवन पर प्रदर्शन किया। हितों की बात थी, सो दोनों संगठनों ने मिलकर सरकार से १६ दिन तक रस्साकशी की। उस हड़ताल में मुख्यमंत्री ने बातचीत और समझौता वार्ता में बी०एन० सिंह को तरजीह दी। यही वजह थी कि कर्मचारी शिक्षक महासंघ के बजाय राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समझौते का श्रेय हासिल कर लिया था।

पृष्ठभूमि : २६ नवम्बर, १९८६ को सरकार से हुई समझौता-वार्ता के बाद ७०१ रुपए की न्यूनतम वेतन की उपलब्धि हुई थी। उस समय केन्द्र के समान न्यूनतम वेतन ७५० रुपए की मांग पर फैसला करने के लिए सरकार ने एक वेतन समिति गठित कर दी थी। दरअसल, वेतन समिति की रिपोर्ट में हुआ विलम्ब ही इस हड़ताल का मूल कारण था। पहले तय था कि २९ मई, १९८७ तक वेतन समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट ३० जून तक प्रकाशित और लागू कर दी जायेगी।

इसी बीच २६ और २७ मई को कर्मचारी-शिक्षक महासंघ ने बेगम हजरत महल पार्क में सभा और रैली का आयोजन करने की घोषणा कर दी। सरकार की नजर में यह रैली इसलिए आंख की किरकिरी साबित हुई, क्योंकि महासंघ ने उसमें पूर्व रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन दिनों बड़े जोरशोर से अभियान चलाया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रदेश में पांव नहीं जमाने देंगे। महासंघ की रैली में उनके आने की पुष्टि के बाद ही पूरे जिले में धारा १४४ लगाकर रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्क में कर्मचारियों की जगह पुलिस और पी०ए०सी० का भारी जमावड़ा था। राजा आये और कार से ही पूरे पार्क का चक्कर लगाकर वापस हो लिये। इसी के बाद ७ जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर वेतन समिति को रिपोर्ट देने की अवधि ३१ मार्च, १९८८ तक बढ़ा दी गयी। कर्मचारियों ने इसे अपने साथ सरकार की धोखाधड़ी माना। इसी बीच सरकार ने विधानसभा अधिवेशन के दौरान अपने विधायकों के वेतन और सहूलियतों में दो गुना से ज्यादा की वृद्धि कर दी। कुल ३० माह तक जिंदा रहनेवाली विधानसभा के सदस्यों का वेतन २५५० रुपए से बढ़ाकर ४०५० रुपए करने में एक भी दिन का समय नहीं लगा। इसके अतिरिक्त इन विधायकों को एक लाख रुपए ब्याज रहित कर्ज देने की व्यवस्था तथा हवाई जहाज से यात्रा की सुविधा भी मुहैया करा दी गयी।

वेतन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने में विलम्ब और विधायकों की वेतनवृद्धि व सहूलियतों की घोषणा ने कर्मचारियों के आक्रोश में घी का काम किया। राज्य-कर्मचारी शिक्षक महासंघ ने हमेशा की तरह इस बार भी रैली करने की घोषणा कर दी। १५ सितम्बर को महासंघ ने रैली के साथ अपनी सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने के लिए सचिवालय की ओर रुख किया, तो वीर बहादुर की सरकारी पुलिस और पी०ए०सी० ने लाठियां बरसाकर और घोड़े दौड़ाकर कर्मचारियों के आक्रोश को कुचलने की पुरानी ऐतिहासिक गलती कर दी। नतीजतन सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी नेता दिनेश कुमार श्रीवास्तव की मौत हुई। ७२ घंटों की सांकेतिक हड़ताल के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

सरकारी दावं-पेंच : सरकार ने बातचीत से आक्रोश शांत करने के बजाय दावं-पेंच का रास्ता अख्तियार किया। गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने इस हड़ताल के पीछे विश्वनाथ प्रताप सिंह का इशारा बताया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर ने भी हड़ताल के प्रति कोई निश्चित रुख प्रकट न करते हुए पूर्व की भांति मंत्रिमंडलीय उपसमिति को आगे कर दिया।

राज्य-कर्मचारी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष लल्लन पाण्डेय का कहना था, "सरकार ने विधायकों के वेतन और सहूलियतों को दो गुना से भी ज्यादा बढ़ाने में तो उदारता की हद कर दी, लेकिन कर्मचारियों व शिक्षकों की मांगों को घोड़े की टापों तले रौंदना चाहती है।"

महासंघ के महासचिव जागेश्वर यादव तथा शिक्षकों के नेता मांधाता सिंह का कहना था,

"राज्य-कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन देने पर सरकार पर ४७० करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार की बात शासन ने कही थी। इसमें से १३० करोड़ रुपए तो शासन को भविष्यनिधि में वापस मिल जायेगा। बाकी के ३४० करोड़ रुपए में से नवम्बर में हुए समझौते के अनुसार २८० करोड़ रुपए अंतरिम राहत के रूप में सरकार दे चुकी है। इस प्रकार केवल ६० करोड़ रुपए राज्यकर्मियों को और देने के लिए सरकार ने वेतन समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट आने में अनावश्यक विलम्ब करना सरकार की तरफ से कर्मचारियों के प्रति धोखाधड़ी करना ही है।"

इन तर्कों के विपरीत सरकार ने समझौता वार्ता चलाने की जगह हड़ताल तोड़ने की सारी कोशिशें कर डालीं। धमकी व चेतावनी के साथ ही कर्मचारी, शिक्षकों के दूसरे बड़े संगठन राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा कर्मचारी समन्वय समिति को मुख्यमंत्री ने हड़ताल से विलग करवा दिया। इन दोनों के सर्वेसर्वा उनके चहेते बी०एन० सिंह ही हैं। सचिवालय कर्मचारियों को हड़ताल में न शामिल होने देने के लिए हड़ताल के मध्य ही वहां के क्लर्कों और सेक्शन आफीसरों के वेतन में ३० रुपए से लेकर ५० रुपए तक की वृद्धि कर दी।

राज्य-कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष बी०एन० सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मुख्यमंत्री ने एम०एल०सी० बनाने का प्रलोभन दे रखा है। शायद इसी कारण पिछले उपचुनाव में बी०एन० सिंह ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर हरिद्वार, प्रतापगढ़ और हमीरपुर का चुपचाप दौरा भी किया। उन्होंने परिषद से सम्बन्धित कर्मचारियों को चुनाव जितवाने के लिए प्रेरित किया था। बी०एन० सिंह यद्यपि अब सरकारी सेवाओं में भी नहीं हैं, तथापि संयुक्त परिषद तथा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के सर्वेसर्वा हैं।

महासंघ के एक पदाधिकारी का आरोप है कि मुख्यमंत्री के प्रति इसी भक्ति के कारण बी०एन० सिंह ने राज्य कर्मचारी और शिक्षकों पर सरकारी दमन की न तो खुलकर भर्त्सना की और न ही उनका साथ ही दिया। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के सुर-में-सुर मिलाकर यह फतवा भी दे डाला कि इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में बी०एन० सिंह का कहना था, "इस भयंकर सूखे के समय हड़ताल करना नैतिकता के विरुद्ध है। हमने १३ नवम्बर से इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा पहले ही कर रखी थी। महासंघ ने श्रेय प्राप्ति के लिए असमय यह हड़ताल की, इसलिए हम उनका साथ नहीं दे सकते।"

दूसरी ओर कर्मचारी शिक्षक महासंघ के प्रति सरकारी दमन के पीछे यह समझा जाता है कि २७ मई की रैली में वी०पी० सिंह को बुलाने के एवज में मुख्यमंत्री, महासंघ के नेताओं को सबक सिखाना चाहते थे। महासंघ के एक नेता मांधाता सिंह विधान परिषद में मुख्यमंत्री के मुखर आलोचक रहे हैं। लल्लन पाण्डेय ने वी०पी० सिंह और कमलापति के बीच सम्पर्क का काम अंजाम दिया था। यही वजह थी कि हड़ताल के अनिश्चितकालीन हो जाने के बावजूद मुख्यमंत्री कोई गम्भीरता बरतने के बजाय यही कहते रहे कि प्रदेश में हड़ताल का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी ओर स्थिति यहां तक आ पहुंची कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला इकाइयां टूटकर हड़ताल में शामिल होने लगीं।

वीर बहादुर का मोहरा: बी०एन० सिंह

समझौता कैसे हुआ: पिछली हड़ताल का रिकार्ड जब इस हड़ताल ने तोड़ दिया, तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री की खुमारी टूटी। इसी के बाद बीसवें दिन ५ अक्तूबर की रात से मंत्रिमंडलीय वेतन उपसमिति में समझौता वार्ता का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ६ अक्तूबर को देर रात कर्मचारी शिक्षक महासंघ ने पहली बार श्रेय हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। समझौते के अनुसार राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय तथा निगमों सहित वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतन लाभ दिया गया। अन्तरिम सहायता वेतन भी ७ प्रतिशत की दर से न्यूनतम ४५ रुपए तथा अधिकतम १४० रुपए की वेतन बढ़ोत्तरी एक सितम्बर से लागू की गयी। इस प्रकार ७४६ रुपए न्यूनतम वेतन पर आकर समझौता हुआ। वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन भत्ते में ४५ रुपए की अंतरिम सहायता की घोषणा के साथ इन कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धी मामला भी वेतन समिति के हवाले कर दिया गया। वेतन सम्रिति की रिपोर्ट भी १५ दिसम्बर, १९८७ तक प्रकाशित करने का वायदा सरकार ने किया।

कर्मचारी शिक्षक महासंघ की इस उपलब्धि से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की साख गिरी थी। अतः परिषद तथा समन्वय समिति के सर्वेसर्वा बी०एन० सिंह ने समझौते के अगले ही दिन मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी साख को गिरने से बचाने का आग्रह किया। आनन-फानन एक ज्ञापन बना और मुख्यमंत्री ने अपनी इस गोट को समझौता शर्तों के ऊपर फिट कर दिया। बी०एन० सिंह के ज्ञापन पर मुख्यमंत्री ने समझौता की शर्तों से आगे बढ़कर वेतनवृद्धि में न्यूनतम डेढ़ रुपए और अधिकतम १० रुपए तक का इजाफा कर दिया। इसी के साथ वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी ४५ रुपए के बजाय ७५ रुपए की वेतन-वृद्धि की घोषणा कर दी।

इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का कहना था, "यद्यपि समझौता कर्मचारी शिक्षक महासंघ से हुआ था, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और समन्वय समिति से मिले ज्ञापनों पर मैंने अपने विवेक के आधार पर यह अतिरिक्त अंतरिम राहत देने का फैसला किया है।" इस तरह मुख्यमंत्री ने पिछली बार की तरह इस बार भी अपने चहेते बी०एन० सिंह को हड़ताल की सफलता का श्रेय हासिल कराने में जोड़-तोड़ की राजनीति का सहारा लिया।

अपनी अपनी मजबूरियां: इस प्रकार राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान ७५० रुपए न्यूनतम वेतन प्राप्ति में केवल ढाई रुपए का अन्तर रह गया है। दरअसल महासंघ द्वारा ७४६ रुपए पर समझौता करने तथा सरकार द्वारा इसे मान लेने के पीछे दोनों की अपनी-अपनी मजबूरियां थीं। सचिवालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने भी इसी बीच सचिवालय के बराबर वेतन की मांग को लेकर ८ अक्तूबर से हड़ताल की घोषणा कर दी थी। दूसरे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की १२ अक्तूबर से सांकेतिक हड़ताल की पूर्वघोषणा थी ही। महासंघ के नेताओं का विचार था कि इस हड़ताल में यदि ये लोग भी शामिल हो गये, तो बहुत संभव है कि इस बार भी उन्हें कर्मचारी हितों का श्रेय हासिल करने में गच्चा न खा जाना पड़े। दूसरी ओर सरकार का भी यह सोचना था कि अन्य संगठनों के इस हड़ताल में शामिल हो जाने से स्थिति गम्भीरतम हो जायेगी। यही वजह थी कि ७४६ रुपए पर महासंघ और सरकार का समझौता हो गया। बाद में मुख्यमंत्री ने संयुक्त परिषद के ज्ञापन पर भी वेतन-वृद्धि की घोषणा कर उन्हें शान्त कर दिया।

यही कारण था कि महासंघ के समझौते को कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों ने नहीं माना। उच्च न्यायालय कर्मचारी संगठन ने महासंघ के नेता लल्लन पाण्डेय और मांधाता सिंह को घेर कर अपना रोष प्रकट किया। उन लोगों का कहना था कि हड़ताल इतनी खिंच गयी थी, तो और आगे बढ़ायी जा सकती थी। ७५० रुपए न्यूनतम वेतन की मांग पर सरकार को झुकाया जा सकता था। बार-बार हड़ताल करना भी कहां तक न्यायोचित है।

फिलहाल ढाई रुपए के अन्तर को पूरा कराने के लिए प्रदेश के दोनों कर्मचारी संगठनों ने भविष्य की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सरकार के इस राजनीतिक दावपेंच के कारण सूखे की इस भयंकर स्थिति में राहत का कार्य इस हड़ताल के दौरान ठप पड़ा रहा।

—सुरेश द्विवेदी

छाया: किशन सेठ

पद्मा सेठ, नगर विकास राज्यमंत्री

ठेकों की राजनीति

सीतापुर जिले में बिसवां एक छोटा-सा कस्बा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नगर विकास राज्य मंत्री पद्मा सेठ का चुनाव क्षेत्र होने के कारण उन्होंने इसे सारे कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर संगठित नगर विकास योजना के अंतर्गत शामिल करवा लिया और लाखों रुपए की विकास योजनाएं वहां चालू हो गयीं। इससे क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये विकास योजनाएं ही वहां की जनता में श्रीमती सेठ के विरुद्ध तीव्र आक्रोश पैदा करने का कारण बन रही हैं? उन पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि उनके ही प्रतिनिधि, उनकी ही शह पर घोटाले करके विकास योजनाओं में लग रहे धन से अपनी जेबें भर रहे हैं?

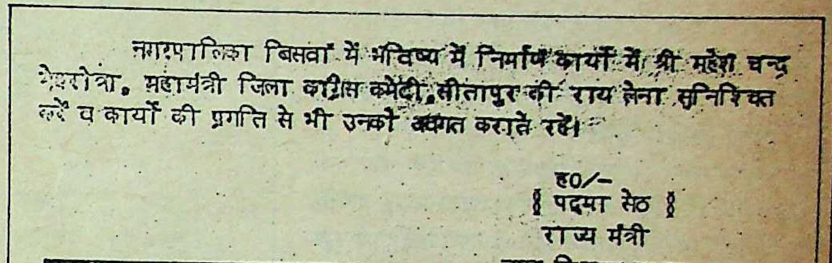

नगरपालिका बिसवां में भविष्य में निर्माण कार्यों में श्री महेश चन्द्र मेहरोत्रा, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, सीतापुर की राय लेना सुनिश्चित करें व कार्यों की प्रगति से भी उनको अवगत कराते रहें।

ह0/-
(पद्मा सेठ)
राज्य मंत्री
नगर विकास,उ0प्र0

मेहरोत्रा की अहमियत: श्रीमती सेठ (बायें) द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गये पत्र के अंश (ऊपर)

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौसी और भूतपूर्व आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री अरुण नेहरू की फूफी श्रीमती पद्मा सेठ का नेहरू परिवार से जुड़े होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार में रुतबा कम नहीं है। वह नगर विकास राज्यमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र बिसवां (सीतापुर) में कड़े जनविरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, बिसवां नगरपालिका द्वारा दिये गये ठेकों में हुए घपलों के कारण ही यह विरोध उग्र रूप धारण करता जा रहा है। बिसवां कस्बे की दीवारें श्रीमती सेठ पर लगाये गये लांछनों से जब तब रंग उठती हैं। ठेकों के घोटालों में सीतापुर जिला कांग्रेस-इ कमेटी के महामंत्री महेश चंद्र मेहरोत्रा का नाम प्रमुख रूप से उछाला है और श्री मेहरोत्रा वहां श्रीमती पद्मा सेठ के प्रतिनिधि की हैसियत से अपना दबदबा कायम किये हुए हैं। श्रीमती सेठ के राजनीतिक विरोधियों ने भी मौके का फायदा उठाकर उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री बनते ही श्रीमती सेठ ने अपने चुनाव क्षेत्र बिसवां में अपना जनाधार मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक छोटा कस्बा होने के बावजूद श्रीमती सेठ बिसवां को केंद्र सरकार की संगठित नगर विकास योजना में शामिल कराना चाहती थीं, जिससे क्षेत्र विकास के लिए धन की व्यवस्था हो सके, लेकिन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नरेंद्र स्वरूप जौहरी ने ७ जून, १९८५ को उत्तर प्रदेश सरकार के आवास अनुभाग को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि बिसवां इतनी छोटी बस्ती है कि वह संगठित विकास योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए निर्धारित जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती, इसलिए इसे इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि फिर श्री जौहरी की उक्त टिप्पणी को बदलवाने के लिए अरुण नेहरू के असर का इस्तेमाल हुआ। इसका असर यह हुआ कि एक मास से भी कम समय में अर्थात १ जुलाई, १९८५ को श्री जौहरी ने अपनी रिपोर्ट बदल दी। इस प्रकार पहली अप्रैल, १९८६ से संगठित नगर विकास योजना बिसवां में लागू हो गयी।

घपलों की शुरुआत: इस योजना के अंतर्गत हरिजन एवं मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से विद्युतीकरण, पेयजल के लिए पाइप लाइनों का बिछाना, व्यावसायिक काम्प्लेक्स एवं लैंप पोस्टों का निर्माण सहित अनेक योजनाएं शामिल थीं। बिसवां नगरपालिका ने सभी योजनाओं के लिए कई चरणों में खर्च करने के लिए १८५ लाख रुपए का बजट पारित किया। श्रीमती सेठ चाहती थीं कि इन योजनाओं का काम उनके प्रतिनिधि की देखरेख में हो। इसके लिए उन्होंने २१ अप्रैल, १९८६ को सीतापुर के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर निर्देश दिया, "नगरपालिका बिसवां में भविष्य में निर्माण कार्यों में श्री महेश चंद्र मेहरोत्रा की राय लेना सुनिश्चित करें और कार्यों की प्रगति से भी उनको अवगत कराते रहें।" जिलाधिकारी ने ३० अप्रैल, १९८६ को बिसवां के परगनाधिकारी तथा नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को राज्यमंत्री के इन आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिये। साथ ही यह आदेश जारी किया कि जब भी नगरपालिका का कोई प्रस्ताव बने, तब महेश चंद्र मेहरोत्रा से संपर्क हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाये। इसी के बाद नगरपालिका में महेश चंद्र मेहरोत्रा की तूती बोलने लगी। २४ नवंबर, १९८६ को बिसवां नगरपालिका ने विद्युत विभाग से बिसवां में ८० विद्युत पोल लगाने हेतु अनुमानित खर्च मांगा। विद्युत विभाग ने १९ दिसंबर, १९८६ को यह खर्च ८० हजार, ८ सौ, ६१ रुपए बताया, जिसे १७ जनवरी, १९८७ को विद्युत विभाग ने संशोधित कर ९४ हजार, एक सौ रुपए कर दिया।

इसी दौरान संगठित विकास योजना के तहत बिसवां की तीन मलिन बस्तियों झज्जर, जोशी टोला और काजी टोला में विद्युत पोल लगाने का ठेका दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक ओर विद्युत विभाग ने ८० पोल लगाने का खर्च ९५ हजार रुपए निश्चित किया था, वहीं मात्र ५२ विद्युत पोल लगाने के लिए मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग द्वारा प्रस्तुत चार लाख, एक हजार रुपए का टेंडर मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक नरेंद्र स्वरूप जौहरी ने स्वीकृत कर लिया। विद्युत विभाग के अनुसार इन ५२ विद्युत पोलों को लगाने में मात्र ५७ हजार, ५ सौ, ५२ रुपए खर्च होने थे। २० फरवरी, १९८७ को विद्युत पोल लगाने का कार्य जारी हुआ और ७ मार्च, १९८७ को पूर्ण हो गया। उधर ७

मार्च, १९८७ को ही विद्युत विभाग ने नगरपालिका बिसवां को एक पत्र लिखकर विद्युत पोल लगाने का कार्य रोकने का अनुरोध किया। विद्युत विभाग को शक था कि उक्त पोल विद्युत विभाग से ही चोरी किये गये हैं और उन पोलों से विद्युत विभाग का ट्रेडमार्क खुरच दिया गया है।

नगरपालिका के अधिकारियों ने विद्युत विभाग की आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु जब २६ अप्रैल, १९८७ को एक हिंदी दैनिक के बिसवां स्थित संवाददाता ने एक समाचार के जरिये आरोप लगाया कि मिर्जा सुलेमान बेग द्वारा लगाये गये पोल विद्युत विभाग से ही चुराये गये थे, तो बिसवां में पद्मा सेठ के खिलाफ पोस्टर और पर्चे चिपकाये गये, जिनमें आरोप लगाया गया था कि मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग द्वारा लिये गये ठेके वास्तव में महेश चंद्र मेहरोत्रा के साले सुशील टंडन के थे। इस ठेकेदारी में महेश चंद्र मेहरोत्रा की भागीदारी भी थी।पद्मा सेठ के प्रभाव के कारण ही महेश चंद्र मेहरोत्रा नगरपालिका के ठेकों से धन उगाही कर रहे थे। इसका परिणाम हुआ कि ८ मई, १९८७ को विद्युत विभाग ने नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को पुनः एक पत्र लिखा कि इस बात की जांच की जाये कि क्या पोल एवं तार वास्तव में विद्युत विभाग के ही हैं।

इस पूरे मामले की जांच कर नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी राजनारायण उपाध्याय ने जो गोपनीय रिपोर्ट सीतापुर के जिलाधिकारी को दी, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार, "मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने मिर्जा मोहम्मद सुलेमान का जो ठेका स्वीकृत किया, उससे नगरपालिका पर ३ लाख, ४४ हजार २ सौ ८८ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार पड़ा है।"

इस जांच रिपोर्ट में महेश चंद्र मेहरोत्रा के बारे में कहा गया कि उधर ७ मार्च, १९८७ से ही महेश चंद्र मेहरोत्रा नगरपालिका के अवर अभियंता पर ठेकेदार मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग द्वारा प्रस्तुत झज्जर मलिन बस्ती के विद्युतीकरण का एक लाख, १६ हजार, दो सौ २३ रुपये का रनिंग बिल पास करने के लिए दबाव डाल रहे थे। अवर अभियंता का कहना था कि बिल में तार का वजन अधिक दर्शाकर ५२ हजार रुपए अधिक के भुगतान का प्रयास कराया जा रहा है। इस मामले में संगठित विकास योजना में कार्यरत लिपिक शब्बीरुल हसन ने २० मई, १९८७ को नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी जे०पी० श्रीवास्तव को एक गोपनीय रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया था, "मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग नामक ठेकेदार को झज्जर मलिन बस्ती में विद्युतीकरण के लिए कटौती के बाद एक लाख, एक हजार, दौ सौ रुपए का भुगतान किया जाना है। वास्तव में यह ठेका नगर विकास मंत्री पद्मा सेठ के प्रतिनिधि महेश चंद्र मेहरोत्रा के साले सुशील टंडन का है। श्री बेग मात्र एक 'डमी' ठेकेदार हैं। श्री मेहरोत्रा इस बिल के भुगतान के लिए बराबर धमकियां देकर दबाव डाल रहे हैं। इस बिल में लगभग ५२ हजार रुपए अधिक दर्शाये गये हैं।"

शिकायत मुख्यमंत्री तक: मई, १९८७ में जब बिसवां के लोगों ने इसकी शिकायत सीतापुर से सांसद तथा केंद्रीय कल्याण राज्य मंत्री डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी से की. तो श्रीमती बाजपेयी ने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से मिलकर उन्हें इन अनियमितताओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश एवं शब्बीरुल हसन की रिपोर्ट के आधार पर अधिशाषी अधिकारी श्रीवास्तव ने ठेकेदार मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग का भुगतान रोकने के निर्देश दे दिये। बस फिर क्या था, श्रीमती पद्मा सेठ का कहर नगरपालिका कर्मचारियों पर टूटने लगा। २८ मई, १९८७ को श्रीमती पद्मा सेठ ने स्वयं बिसवां आकर मौखिक आदेश जारी किये कि शब्बीरुल हसन को तत्काल संगठित विकास योजना से हटाकर नगरपालिका स्कूल भेज दिया जाये। अगले ही दिन एस०डी०एम० सुधाकर अदीब ने शब्बीरुल हसन का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया।

शिकायतों की जांच: संगठित विकास योजना में हो रहे घपलों की शिकायतों की जांच करने स्थानीय निकाय की उपनिदेशक श्रीमती संध्या तोमर १५ जून, १९८७ को स्वयं लखनऊ से बिसवां गयीं। श्रीमती तोमर ने भी संगठित विकास योजना के तहत किये गये विद्युत विस्तार, पाइप लाइनों के निर्माण एवं स्टैण्ड पोस्टों के निर्माण कार्य में अत्यधिक अनियमितताएं पाकर संबंधित ठेकेदार को भुगतान न करने के आदेश जारी किये। श्रीमती तोमर को दिये गये बयान में दो अवर अभियंताओं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि मलिन बस्तियों में लैम्प पोस्ट का निर्माण, पाइप लाइन बिछाने एवं विद्युतीकरण का कार्य ठेकेदार मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग को दिया गया था, पर सारा कार्य लखीमपुर निवासी सुशील टंडन ने कराया। सुशील टंडन और महेश चंद्र मेहरोत्रा ने हम पर कार्य को मेजरमेंट बुक में चढ़वाकर भुगतान कराने का दबाव डाला। असमर्थता प्रगट करने पर महेश चंद्र मेहरोत्रा ने हमें नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। श्रीमती संध्या तोमर ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिये। निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जो शिकायत इन लोगों ने की थी, उसकी जांच के लिए पांच दिन बाद २० जून को श्रीमती पद्मा सेठ ने स्थानीय निकाय के निदेशक प्रीतम सिंह को बिसवां भेजा। श्री सिंह ने तत्कालीन आदेश से उसी दिन नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी जे०पी० श्रीवास्तव को दोषी पाकर स्थानांतरित कर दिया। अगले दिन श्रीमती पद्मा सेठ ने बिसवां जाकर स्वयं कैश बुक और चेक बुक 'सील' (निरक्षण) कर दी, ताकि पिछली तिथियों में ठेकेदारों को भुगतान न किया जा सके।

फर्जी बिल: बिसवां के तहसीलदार राज नारायण उपाध्याय को २२ जून, १९८७ से नगरपालिका के कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी का कार्य भार सौंप दिया गया। श्री उपाध्याय ने मामले की जांच की, तो ज्ञात हुआ कि ठेकेदार मिर्जा मोहम्मद सुलेमान बेग द्वारा प्रस्तुत अधिकांश बिल

महेशचंद्र मेहरोत्रा

महेश चंद्र मेहरोत्रा ने बताया कि यह सब कुप्रचार श्रीमती पद्मा सेठ व मुझे बदनाम करने के लिए डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का गुट तथा पूर्व विधायक रामकुमार भार्गव कर रहे हैं। चुनाव के समय से ही श्री भार्गव हमारे विरोधी बन गये थे, क्योंकि उनका टिकट कट गया था। जब मैंने देखा कि नगरपालिका में २६ प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है, तो मैंने इसकी शिकायत श्रीमती पद्मा सेठ से की। गत वर्ष एक लाख की लागत से बना रायगंज नाला पहली बरसात में ढह गया, तो मैंने मंत्रीजी से शिकायतकर उसकी जांच करवायी थी।

फर्जी हैं। लखनऊ की जिस फर्म 'भारत इलेक्ट्रिकल्स कंपनी' के नाम की रसीद प्रस्तुत की गयी थी, उस फर्म का कोई वजूद नहीं था। बिक्री कर विभाग ने भी बिल में दर्शाया फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी बताया। उधर लखीमपुर खीरी (पलिया) की 'राज कांस्ट्रेक्शन कंपनी' द्वारा जारी रसीद की तिथि ७ मई, १९८७ के स्थान पर २ मई, १९८७ कर दी गयी थी। जांच में यह बात सिद्ध हो गयी, इतना ही नहीं जिस 'रामा ट्रांसपोर्ट कंपनी' द्वारा लखीमपुर से बिसवां बिजली के खम्बे लाना दर्शाया गया था, वह भी फर्जी कंपनी निकली।

उधर २८ जुलाई, १९८७ को मिर्जा मो० सुलेमान बेग ने बिसवां के मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान दे दिया कि मैं नाममात्र का ठेकेदार हूं। विद्युत विस्तार एवं पाइप लाइन बिछाने का सारा कार्य महेश चन्द्र मेहरोत्रा के साले सुशील टंडन ने स्वयं कराया है। मुझे मात्र चौथाई लाभांश मिलने की बात थी जो नहीं मिली है। मुझे अभी तक जितना भुगतान नगरपालिका ने किया है, वह सब मैंने सुशील टंडन को दे दिया था।

जांच अधिकारी राजनारायण उपाध्याय ने जांच के दौरान मिर्जा मो० सुलेमान् बेग, सुशील टंडन और महेश चंद्र मेहरोत्रा को दोषी पाया। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पहली अगस्त, १९८७ को इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध बिसवां कोतवाली में विद्युत विभाग से चोरी के पोल लाकर उनके फर्जी बिल नगरपालिका में दाखिलकर नगरपालिका को धोखा देने एवं नुकसान पहुंचाकर अनुचित लाभ कमाने, जान-बूझकर फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने, अभिलेखों में हेराफेरी करने तथा गिरोह बनाकर नगरपालिका से धन निकालने की रिपोर्ट श्री उपाध्याय ने दर्ज करायी। राजनारायण उपाध्याय द्वारा लिखाई इस रिपोर्ट से बिसवां कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने ४२०, ४११, ३७५ जैसी गंभीर धाराएं हटा दीं। श्री उपाध्याय का कहना है कि पुलिस ने महेश चंद्र मेहरोत्रा को बचाने के लिए ऐसा किया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस रिपोर्ट पर पुलिस ने कोई कार्यवाही भी नहीं की।

आरोप और भी हैं: श्रीमती पद्मा सेठ और महेश चंद्र मेहरोत्रा पर और भी कई गंभीर आरोप हैं। बिसवां के शमीम कौसर (सिद्दीकी) कांग्रेस कैडर बिल्डिंग के ब्लाक प्रशिक्षक एवं महामंत्री हैं। उनके पिता फारूख आजम समर बिसवानी, बिसवां लायर्स बार एसोसिएशन के सचिव और सीतापुर कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के महामंत्री हैं। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का समर्थक होने के कारण इन दोनों को श्रीमती पद्मा सेठ का कोपभाजन बनना पड़ा। डा० बाजपेयी और पद्मा सेठ दोनों ही सीतापुर में अपना दबदबा कायम करना चाहती हैं। १९८५ के विधान सभा चुनाव में पूर्व विधायक रामकुमार भार्गव को टिकट दिये जाने की घोषणा हो गयी। पर नामांकन के पूर्व ऐन मौके पर अरुण नेहरू ने पद्मा सेठ को टिकट देकर श्री भार्गव का टिकट काट दिया। महेश चन्द्र मेहरोत्रा ने भी टिकट मांगा था। पद्मा सेठ का नाम आते ही महेश चन्द्र मेहरोत्रा ने अपना दावा वापस ले लिया और यह आरोप लगाया कि राम कुमार भार्गव और उनके समर्थक सांसद राजेंद्र कुमारी बाजपेयी के खास हैं। वह श्रीमती बाजपेयी के इशारे पर पद्मा सेठ का विरोध कर रहे हैं। इसके पूर्व श्री मेहरोत्रा श्रीमती बाजपेयी के कट्टर समर्थकों में थे। मेहरोत्रा के आरोप लगाते ही अरुण नेहरू ने श्री भार्गव से फोन पर पद्मा सेठ के समर्थन में प्रचार करने का आग्रह किया। श्री भार्गव के विधायक चुने जाने के पूर्व बिसवां जनसंघ का गढ़ था। रामकुमार भार्गव ही जनसंघ के अधिकांश समर्थकों को कांग्रेस में ले आये थे। उनकी बिसवां में अच्छी छवि थी।

फिलहाल पद्मा सेठ चुनाव जीत गयीं। जब रामकुमार भार्गव के समर्थक क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में श्रीमती पद्मा सेठ से मिले, तो उनका उत्तर था, "तुम लोग राजेंद्र कुमारी बाजपेयी और रामकुमार भार्गव के समर्थक हो। शहर कांग्रेस कमेटी मेरा विरोध करती है। तुम अपने राजनीतिक आकाओं के पास जाओ।"

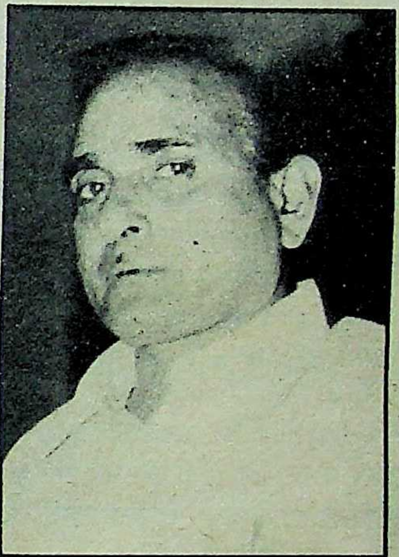

राजनारायण उपाध्याय

जांच अधिकारी राजनारायण उपाध्याय ने जांच के दौरान मिर्जा मो० सुलेमान बेग, सुशील टंडन और महेश चंद्र मेहरोत्रा को दोषी पाया। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पहली अगस्त, १९८७ को इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध बिसवां कोतवाली में विद्युत विभाग से चोरी के पोल लाकर उनके फर्जी बिल नगरपालिका में दाखिलकर नगरपालिका को धोखा देने एवं नुकसान पहुंचाकर अनुचित लाभ कमाने, जान-बूझकर फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने, अभिलेखों में हेराफेरी करने तथा गिरोह बनाकर नगरपालिका से धन निकालने की रिपोर्ट श्री उपाध्याय ने दर्ज करायी।

बिसवानी का मामला: इसी घटना के बाद कहा जाता है कि राजेंद्र कुमारी बाजपेयी और श्रीमती पद्मा सेठ में ठन गयी। बिसवां में श्रीमती सेठ का राजनीतिक विरोध भी होने लगा। समर बिसवानी का आरोप है, "संगठित विकास योजना लागू होने के बाद जब महेश चंद्र मेहरोत्रा को श्रीमती सेठ ने असीमित अधिकार सौंपे, तो श्री मेहरोत्रा ने ठेकेदारी के जरिये नगरपालिका में अनियमितताएं शुरू कर दीं। हमने इसका जुबानी विरोध किया। हमें सबक सिखाने के उद्देश्य से महेश चन्द्र मेहरोत्रा ने लहरपुर रोड पर स्थित जलालपुर ग्राम सभा के कब्रिस्तान एवं खलिहान पर जलालपुर चौराहा सौंदर्यीकरण योजना के तहत दुकानें बनवानी शुरू कर दीं। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह कब्रिस्तान काश्तकार खलिहान के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के पूर्व फातिहा और मीलाद भी यहीं होता था।"

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उक्त जमीन उर्दू के मशहूर शायर वासिद बिसवानी की थी। वासिद बिसवानी की मृत्यु १९३८ में हुई थी। वह पहले ऐसे शायर थे, जिनकी शायरी किसी फिल्म में बतौर गीत ली गयी। फिल्म 'जुगनू' में 'हमें तो शामे गम में काटनी है, जिंदगी अपनी', गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था। इतना ही नहीं वासिद बिसवानी कौमी एकता की बात करनेवाले पहले उर्दू शायर थे, उनके गीत 'उनका कोई नहीं गैर बाबा', का रिकार्ड भी बहुत लोकप्रिय हुआ था।

आरोप है कि इस जमीन पर कब्जे के बाद समर बिसवानी के खेतों को भी महेश चंद्र मेहरोत्रा ने नगरपालिका की संपत्ति बता कर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब श्री बिसवानी ने विरोध किया, तो उन्हें एक रिक्शाचालक परागी व राजगीर दूबर के साथ तीन फुट की दो बल्ली चोरी करने के आरोप में फांस दिया गया। पद्मा सेठ के प्रभाव में आकर

साक्षात्कार/श्रीमती पद्मा सेठ, नगर विकास राज्यमंत्री

'मुझे राजनीतिक दुश्मनी के कारण बदनाम किया जा रहा है'

उत्तर प्रदेश की नगर विकास मंत्री श्रीमती पद्मा सेठ बिसवां में हो रहे अपने विरोध को राजनीतिक शत्रुता के तहत रचे गये षड्यंत्र की संज्ञा देती हैं। बिसवां नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करते ही श्रीमती सेठ ने कहा, "यह सारा कुप्रचार बिसवां के पूर्व विधायक राम कुमार भार्गव मात्र इसलिये कर रहे हैं, क्योंकि विधान सभा से उनका टिकट काटकर मुझे दिया गया था।" 'माया' द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर श्रीमती सेठ ने इस प्रकार दिये—

माया: क्या आपने बिसवां में अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है?

श्रीमती सेठ: नहीं।

माया: लेकिन महेश चन्द्र मेहरोत्रा स्वयं को बिसवां में आपका प्रतिनिधि बताते हैं। इतना ही नहीं आपने नगर पालिका के कार्यों में श्री मेहरोत्रा की राय लेना और कार्यों की प्रगति से उन्हें अवगत कराते रहने के निर्देश भी दिये हैं। ऐसा आरोप है?

श्रीमती सेठ: मैंने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये कि नगर पालिका के कार्यों में महेश चन्द्र मेहरोत्रा की राय ली जाये, या कार्यों की प्रगति से उन्हें अवगत कराते रहा जाये। हां, इतना अवश्य है कि यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग स्थानीय समस्या लेकर मेरे पास आते हैं, तो उन्हें मैं महेश चन्द्र मेहरोत्रा के पास निराकरण करवाने के लिए भेज देती हूं। वह भी इसलिए क्योंकि महेश कांग्रेस का एक कर्मठ कार्यकर्ता है। मैं अपने क्षेत्र में बहुत कम जा पाती हूं। जब मैं बिसवां चुनाव लड़ने गयी थी, तो वहां के लिए नयी थी। कुछ नहीं जानती थी। महेश ने ही मुझे चुनाव लड़वाकर जितवाया था। इसी कारण मेरे राजनीतिक विरोधी उसके पीछे पड़े हैं।

माया: बिसवां नगरपालिका में संगठित विकास योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों में काफी अनियमितताओं की शिकायते हैं?

श्रीमती सेठ: मेरी नजर में जैसे ही यह बात आयी, मैंने जाच के आदेश जारी कर दिये। जो कोई भी दोषी पाया जायेगा, उसे सजा मिलेगी।

माया: आरोप है कि आपके प्रभाव का लाभ उठाकर महेश चन्द्र मेहरोत्रा ने अपने कुछ विरोधियों की जमीनों पर नगर पालिका का कब्जा करवा दिया है।

श्रीमती सेठ: आप समर बिसवानी की बात कर रहे होंगे। उस मामले में डी०एम० और एस०डी०एम० की जांच से सिद्ध हो चुका है कि जमीन उनकी नहीं नगरपालिका की थी। फिर बिसवानी ने अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। यदि अदालत उनकी जमीन बताती है, तो उन्हें दे दी जायेगी। हां, इस मामले में महेश चन्द्र मेहरोत्रा को जबरन खींचा गया है। वास्तव में समर बिसवानी-रामकुमार भार्गव मिलकर ही हमारे हर काम में अड़चन डालते हैं। राम कुमार भार्गव की वजह से मुझे हैरान करने के लिए मेरे खिलाफ गन्दे पोस्टर और पर्चे छापे गये। सारी राजनीतिक दुश्मनी तो मुझसे है। जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाये तो मेरा समर्थक होने की वजह से महेश चन्द्र पर बेबुनियाद आरोप लगा कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं।

माया: लेकिन मेहरोत्रा पर अपने साले को फर्जी नाम से ठेका दिलवाने और भुगतान के लिए नगरपालिका कर्मचारियों पर दबाव डालने की शिकायतें हैं?

श्रीमती सेठ: ऐसी कोई शिकायत मेरी नजर में नहीं आयी है।

माया: कहा जा रहा है कि विभागीय आपत्ति के बाद भी बिसवां में संगठित विकास योजना लागू की गयी?

श्रीमती सेठ: कोई विभागीय आपत्ति नहीं है। फिर वे कौन होते हैं आपत्ति करनेवाले! यह केन्द्र की योजना है, केन्द्र मुझसे योजना लागू करने के लिए शहरों के नाम मांगता है, मैं भेज देती हूं।

माया: चर्चा है कि आपका सांसद डा० श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी से भी मतभेद चल रहा है। उन्होंने बिसवां नगर पालिका में निर्माण कार्यों में भी अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी?

श्रीमती सेठ: देखिये, मुझे राजेन्द्री जी से कोई शिकायत नहीं है। वह हमारी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती हूं। रही मुख्यमंत्री से शिकायत की बात, तो राम कुमार भार्गव श्रीमती बाजपेयी से जो कह देते हैं, श्रीमती बाजपेयी उसे सच मानकर मुख्यमंत्री से कह देती हैं। जबकि श्रीमती बाजपेयी से सचाई छिपायी जाती है।

माया: नगरपालिका में अनियमितताओं के लिए महेश चन्द्र मेहरोत्रा और उनके साले की जांच में दोषी पाकर उनके खिलाफ बिसवां कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है?

श्रीमती सेठ: चूंकि, महेश की शिकायत पर तत्कालीन परगनाधिकारी सुधाकर अदीब और नगरपालिका के कर्मचारी शीरा कांड में फंस गये थे। अतः इन सभी ने राम कुमार भार्गव और मेरे विरोधियों से मिलकर मुझे तंग एवं बदनाम करने के लिए महेश चन्द्र मेहरोत्रा को फंसा दिया है। एफ०आई०आर० गलत हुई है। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक मेरे पास आये थे। उनका कहना था कि रिपोर्ट काफी राजनीतिक दबाव डालकर लिखवायी गयी है।

माया: आपका नाम अरुण नेहरू से भी जोड़ा जा रहा है?

श्रीमती सेठ: एक मेरी बहन का लड़का है और दूसरा भाई का बेटा रिश्तेदारी तो दोनों तरफ है। मैं रिश्तेदारों को लेकर कहां चली जाऊं। वैसे राजीवजी को मेरे बारे में पूरी जानकारी है। ये सारी बातें मेरे राजनीतिक विरोधी मुझे बदनाम करने की गरज से कर रहे हैं।

—निशीथ जोशी

पुलिस ने श्री बिसवानी को गिरफ्तार करना चाहा, तो उत्तर प्रदेश बार कौंसिल, सीतापुर बार कौंसिल ने इसका विरोध किया।

संगठित विकास योजना के अंतर्गत इसी दौरान कृपा निधान पार्क को नगरपालिका ने बिजनेस कांप्लेक्स के रूप में बदल डाला। इस बिजनेस कांप्लेक्स में निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताओं की लिखित शिकायतें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता अटल बिहारी बाजपेयी ने कई बार कीं। इस संबंध में श्रीमती पद्मा सेठ से भी कई शिकायतें की गयीं, पर जांच नहीं हुई। यहां के लोगों को आशंका है कि घटिया सामग्री के कारण बिजनेस कांप्लेक्स कभी भी ढह सकता है।

मेहरोत्रा का पक्ष : महेश चन्द्र मेहरोत्रा ने इस संबंध में 'माया' को बताया कि यह सब कुप्रचार श्रीमती पद्मा सेठ व मुझे बदनाम करने के लिए डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का गुट तथा पूर्व विधायक रामकुमार भार्गव कर रहे हैं। चुनाव के समय से ही श्री भार्गव हमारे विरोधी बन गये थे, क्योंकि उनका टिकट कट गया था। जब मैंने देखा कि नगरपालिका में २६ प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है, तो मैंने इसकी शिकायत श्रीमती पद्मा सेठ से की। गत वर्ष एक लाख की लागत से बना रायगंज नाला पहली बरसात में ढह गया, तो मैंने मंत्रीजी से शिकायतकर उसकी जांच करवायी थी। नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी तत्कालीन परगनाधिकारी सुधाकर अदीब एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से प्रतिमाह लाखों रुपयों की शीरे की चुंगी की चोरी कर धन आपस में बांट लेते थे। २७ सितंबर, १९८५ को मैंने इसकी लिखित शिकायत राज्य मंत्री पद्मा सेठ से की थी। इस मामले में कुछ छोटे कर्मचारियों को दंडित किया गया। दोषी अधिकारी और ठेकेदार साफ बच निकले। मेरी शिकायत से इन लोगों की अवैध कमायी बंद हो गयी। परगनाधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है। इस नगरपालिका के ठेकेदार और अधिकारी मेरा विरोध करने लगे। मेरी ही शिकायत पर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी कर्मदेव शर्मा का तबादला हुआ था। संगठित विकास योजना में कार्यरत क्लर्क 'शब्बीरुल हसन' अपने साले एवं मौसी के पुत्र को ठेका दिलाकर अनियमितताएं बरत रहा था। मैंने इसकी शिकायत की, तो मुझे झूठे मामले में फंसा दिया गया। नगरपालिका में न तो मेरे साले सुशील टंडन का कोई बेनामी ठेका है और न ही कोई हिस्सेदारी। रही समर बिसवानी के यहां कब्जे की बात, तो वह नगरपालिका ने कराया है। मैं बीच में कहां आता हूं। मैंने कई बार स्वयं संगठित विकास योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए बिछाये गये पाइप लाइनों का निरीक्षण किया। लगभग ७०० मीटर पाइप खुदवाकर देखा, तो वे घटिया किस्म के और जरा से दबाव में फट जानेवाले निकले। यह सारा कार्य नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा था। अतः विरोध करने पर मेरे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया गया। परगनाधिकारी सुधाकर अदीब हरिजन समाज कल्याण मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी के रिश्तेदार होने के कारण मेरा और श्रीमती पद्मा सेठ का विरोध करते हैं, क्योंकि मैंने अधिशाषी और परगनाधिकारी के खिलाफ अनियमितताओं की जो शिकायत की थी, उनकी जांच का कार्य इन्हीं दोनों अधिकारियों को सौंप दिया गया। २२ जून को स्वयं श्रीमती पद्मा सेठ ने नगरपालिका की कैश बुक एवं चेक बुक 'सील' की थी। मंत्री द्वारा कोई भुगतान ठेकेदारों को न किये जाने के आदेश के बावजूद अधिशाषी अधिकारी जे०पी० श्रीवास्तव ने परगनाधिकारी सुधाकर अदीब से मिलकर ठेकेदारों को ढाई लाख रुपए का भुगतान किया। यह सब ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत का प्रमाण है। मैंने ही ठेकेदारों खासतौर से मिर्जा मो० सुलेमान बेग का भुगतान रोकने की शिकायत की और मुझे ही उस मामले में कुचक्र रच कर फांस दिया गया। यदि मेरा या मेरे साले का कोई हिस्सा होता, तो मैं भुगतान रोकने की लिखित शिकायत करता।

उधर बिसवां की जनता में भी श्रीमती पद्मा सेठ के खिलाफ आक्रोश भड़क रहा है। पूर्व विधायक राम कुमार भार्गव का कहना है कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि श्रीमती सेठ द्वारा संरक्षण प्राप्त गुण्डों ने महाराज नगर में गरीबों की महिलाओं को उठा ले जाना और फिरौती लेकर छोड़ने का धंधा शुरू कर रखा है। इस मामले में पुलिस भी गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती। बिसवां की सीधी-सादी जनता इसी कारण पद्मा सेठ की विरोधी बन गयी है। पद्मा सेठ मामले को राजनीतिक रंग देकर महेश चन्द्र मेहरोत्रा को बचाना चाहती हैं। इसके प्रमाण में कहा जाता है कि जब एक प्रभावशाली इंका कार्यकर्ता नरेश गौड़ ने पद्मा सेठ का विरोध किया, तो उन्हें पुलिस ने मारपीट के झूठे मामले में फंसा दिया। पद्मा सेठ इन आरोपों को बेबुनियाद बताती हैं।

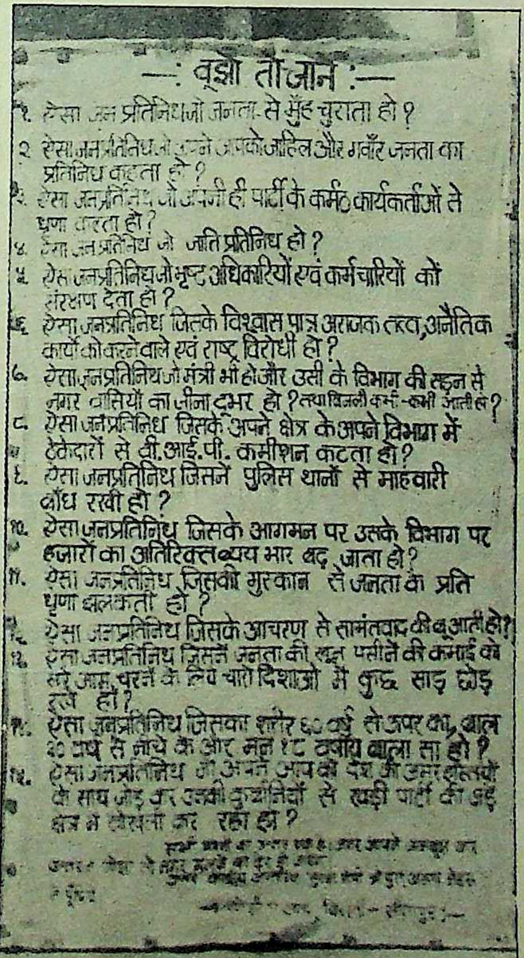

—: बूझो तो जान :—

१. ऐसा जन प्रतिनिधि जो जनता से मुँह चुराता हो ?
२. ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने आपको जाहिल और गवाँर जनता का प्रतिनिधि कहता हो ?
३. ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपनी ही पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से घृणा करता हो ?
४. ऐसा जनप्रतिनिधि जो जाति प्रतिनिधि हो ?
५. ऐसा जनप्रतिनिधि जो भृष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संरक्षण देता हो ?
६. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके विश्वास पात्र अराजक तत्व, अनैतिक कार्यों को करनेवाले एवं राष्ट्र विरोधी हो ?
७. ऐसा जनप्रतिनिधि जो मंत्री भी हो और उसी के विभाग की सड़न से नगर वासियों का जीना दूभर हो ? तथा बिजली कभी-कभी आती हो ?
८. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके अपने क्षेत्र के अपने विभाग में ठेकेदारों से वी.आई.पी. कमीशन कटता हो ?
९. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने पुलिस थानों से माहवारी बाँध रखी हो ?
१०. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके आगमन पर उसके विभाग पर हजारों का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ जाता हो ?
११. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसकी मुस्कान से जनता के प्रति घृणा झलकती हो ?
१२. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके आचरण से सामंतवाद की बू आती हो ?
१३. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने जनता की खून पसीने की कमाई के [illegible] भरने के लिए चारों दिशाओं में गुण्डे साँड़ छोड़ रखे हों ?
१४. ऐसा जनप्रतिनिधि जिसका शरीर ६० वर्ष से ऊपर का, बाल २० वर्ष से नीचे के और मन १८ वर्षीय बाला सा हो ?
१५. ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने आप को देश की [illegible] के साथ जोड़ कर उनकी कुनीतियों से खड़ी पार्टी की [illegible] रहा हो ?

श्रीमती सेठ के खिलाफ बिसवां में लगा एक पोस्टर

राम कुमार भार्गव ने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि महेश चन्द्र मेहरोत्रा के विरुद्ध संगीन आरोप होने के बाद भी राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें गिरफ्तार करने के स्थान पर अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। श्री भार्गव ने 'माया' को बताया, "पद्मा सेठ, महेश चन्द्र मेहरोत्रा के गलत कार्यों का विरोध करनेवाले को अपना राजनीतिक विरोधी करार देकर, उन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं। इतना ही नहीं इस मामले में श्रीमती पद्मा सेठ ने स्वयं मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से मिलकर मामले को दबाने की नीयत से सिफारिश की थी, किंतु मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं हुए," जबकि श्रीमती सेठ का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई सिफारिश मुख्यमंत्री से नहीं की है। पद्मा सेठ के विरुद्ध लोकायुक्त से भी शिकायतें की गयी हैं।

२० जून से रिपोर्ट लिखे जाने तक आधा दर्जन अधिकारियों का तबादला बिसवां नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी के पद पर किया गया है, किंतु कोई भी बिसवां जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पूर्व-अधिशाषी अधिकारियों की तरह महेश चन्द्र मेहरोत्रा के कारण नगर विकास राज्य मंत्री के कोप का शिकार होने का भय है। शायद इसी कारण बिसवां नगरपालिका के कर्मचारी और अधिकारियों के गुट ने श्रीमती पद्मा सेठ के विरोधियों से हाथ मिलाकर उन्हें मदद देना शुरू कर दिया है। पूरी लड़ाई में श्रीमती पद्मा सेठ और महेश चन्द्र मेहरोत्रा और उनके चंद समर्थक अकेले पड़ गये हैं। महेश चंद्र मेहरोत्रा का कहना है, "मैं अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते-लड़ते हिम्मत हार गया हूं। ठेकेदार गुण्डे हैं, अब मैं बिसवां के विकास कार्यों में चाहे जितनी लूटखसोट हो, मैं चुप्पी साधे बैठा रहूंगा।"

दूसरी ओर कांग्रेस-इ का केंद्रीय नेतृत्व वी०पी० सिंह और संजय सिंह की बगावत के बाद आगामी चुनावों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की एक-एक सीट का गणित लगा रहा है। श्रीमती पद्मा सेठ की असली ताकत अरुण नेहरू बेअसर हो चुके हैं, इस वजह से मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी श्रीमती सेठ को संभवतः बहुत अधिक तरजीह नहीं देंगे। श्रीमती सेठ को अब अपने रिश्ते के भतीजे राजीव गांधी का ही भरोसा है, लेकिन वह स्वयं भी तो भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे हैं। श्रीमती सेठ ने स्वयं आगे बढ़कर अपने ऊपर लग रहे लांछनों को नहीं धोया, तो यह सीट आगामी चुनावों में कांग्रेस-इ के हाथ से निकल सकती है।

—निशीथ जोशी

उत्तर प्रदेश में विद्युत विकास

कंप्यूटर तकनीक के वर्तमान परिवेश में जहां बटन दबाने मात्र से बड़े-से-बड़ा कार्य किया जा सकता है, यह कल्पना करना भी कठिन है कि मात्र आठ दशक पहले विद्युत एक अपरिचित वस्तु थी। विद्युत विकास के इतिहास का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत उत्पादनगृह वर्ष १९०३ में एक निजी कंपनी द्वारा मसूरी में बनाया गया था और अगस्त, १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ११४.५६ मेगावाट थी। इसके अतिरिक्त ४२.८३ मेगावाट की क्षमता निजी क्षेत्र में थी।

उद्योग तथा कृषि के विकास एवं सामान्य जन-जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विद्युत की आवश्यकता को समय रहते महसूस किया गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में विशेष प्रयासों के फलस्वरूप आज प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता ४५०५ मेगावाट हो सकी है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सेक्टर में स्थापित विद्युत गृहों से प्रदेश के अंश के रूप में ४५० मेगावाट क्षमता भी उपलब्ध है।प्रदेश के एक कोने से उत्पादन विद्युत को सुदूर क्षेत्रों तक ४,००,२२० तथा १३२ हजार वोल्ट पारेषण लाइनों के माध्यम से उपभोग हेतु पहुंचाया जा रहा है, जबकि १९५०-५५ में पारेषण का कार्य मात्र ६६ हजार वोल्ट पर किया जाता था। विद्युत विकास कार्य पर उचित ध्यान दिया जा सके, इस दृष्टि से वर्ष १९५० में विद्युत विभाग का गठन किया गयातथा विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्युत विकास की दर को और तेज करने की दृष्टि से ही एक अप्रैल, १९५९ को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, १९४८ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। परिषद के प्रारंभिक मुख्य उत्तरदायित्व अविकसित क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना था,जिससे आर्थिक विकास को सुदृढ़ आधार मिल सके और आगे दिए गये विवरण से स्पष्ट है कि परिषद अब तक अपने उद्दश्यों की प्राप्ति में सफल रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि के बाद भी परिषद अभी प्रत्येक खेत को पानी और प्रत्येक ग्राम में विद्युत के अपने लक्ष्य से काफी दूर है। विद्युत की उपलब्धता शीघ्र-से-शीघ्र बढ़ सके, इस अभिप्राय से जहां एक ओर निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है वहीं दूसरी ओर चालू विद्युतगृहों के अधिकतम उपयोग के प्रयास भी किये जा रहे हैं, जिसके लिए ओबरा, पनकी तथा हरदुआगंज तापीय विद्युतगृहों की २७ पुरानी इकाइयों पर लगभग १५७ करोड़ रुपए लागत की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के योजना पर कार्य चल रहा है। मार्च, १९८८ में इस तीन वर्षीय कार्यक्रम के पूरा होने पर इन तापीय इकाइयों से उत्पादन में लगभग १०-१५ प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है।

त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की ओर विद्युत परिषद ने विशेष ध्यान दिया है और इसके फलस्वरूप अगस्त, १९८७ के अंत तक प्रदेश के कुल १,१२,५६८ ग्रामों में से ७२,३०६ ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की यह संख्या ग्रामीण विद्युतीकरण में अग्रणी प्रदेश पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के सम्मिलित कुल विद्युतीकृत ग्रामों से अधिक है, तथापि अभी तक प्रदेश के लगभग ६२ प्रतिशत ग्रामों तक विद्युत पहुंचाई जा सकी है। शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के अपने लक्ष्य को आठवीं योजना के अंत तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है। निजी एवं सरकारी नलकूपों के ऊर्जाकरण की ओर भी काफी प्रयास किए गये। अगस्त, १९८७ के अंत तक इनकी संख्या क्रमशः ५,४७,४४५ तथा २७,३४९ थी। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही उन्हें बिना अतिरिक्त अधिभार के चैफ कटर, राइस हलर तथा थ्रेशर आदि चलाने की भी सुविधा है। विकास का प्रकाश हरिजन बस्तियों तक पहुंच सके, इस दृष्टि से वर्ष १९७१-७२ में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था तथा माह अगस्त, १९८७ तक कुल ४०,७३० हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

हम अपने समस्त उपभोक्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे विद्युत का दुरुपयोग रोकने में सहायक बनें तथा विद्युत उपभोग के बिलों का समय से भुगतान करके बेहतर सेवा का अवसर प्रदान करें।

अनिरुद्ध कुमार शाह
अध्यक्ष
उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद

KRITI/UPSEB/487

ऊर्जा वर्ष 1987

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत का निरंतर प्रवाह

U.P. ELECTRICITY BOARD

गतिशील नेतृत्व के सफल २ वर्ष

प्रदेश में व्याप्त सूखे से संघर्ष करने में विद्युत परिषद किसानों की सहायता में तत्पर है। अधिकाधिक विद्युत उत्पादन करने के अथक प्रयासों से रिकार्ड विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित करके प्रदेश के गाँवों को निर्धारित से अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत परिषद के कीर्तिमानः

गत २० अगस्त १९८७ को विद्युत परिषद द्वारा ४२.४९५ मिलियन यूनिट का रिकार्ड तापीय विद्युत उत्पादन किया गया।

निजी/राजकीय नलकूपों को १० से १२ घण्टे, विश्व बैंक के नलकूपों को १८ घण्टे तथा बड़ी नहरों पर लगे पम्पसेटों को २२ से २४ घण्टे प्रतिदिन की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय/निजी नलकूपों, विश्व बैंक नलकूपों, पम्प कैनाल तथा पेयजल योजनाओं हेतु ७ करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परिषद द्वारा २५०० नये ट्रांसफारमर उपलब्ध कराये गये हैं। इनमें से सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक २०७३ ट्रांसफारमर राजकीय/निजी नलकूपों, पम्प कैनाल व पेयजल योजना को सक्रिय बनाने में लगाए जा चुके हैं।

अगस्त, ८७ तक ४९५० निजी नलकूपों का ऊर्जन हो चुका था तथा सितम्बर ८७ के अन्त तक ७५०० निजी नलकूपों का अर्जन पूर्ण कर लिया जायेगा इसी प्रकार नवम्बर १९८७ तक १०,००० निजी नलकूपों तथा अक्टूबर १९८७ तक ९२ राजकीय नलकूपों के ऊर्जन का लक्ष्य पूरा किया जायेगा जिससे प्रदेश में सिचाई सुविधाओं हेतु सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

अगस्त १९८७ तक विश्व बैंक पोषित १६४ पब्लिक नलकूप ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं तथा अक्टूबर १९८७ के अन्त तक २२८ अतिरिक्त नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है।

चालू वर्ष में अब तक ५० पेयजल योजनाओं का ऊर्जीकृत किया जा चुका है तथा अक्टूबर १९८७ तक ८५ पेयजल योजनाओं का ऊर्जीकरण सम्पूर्ण कर लिया जायेगा।

यह सभी कार्य प्रदेश में व्याप्त सूखे को देखते हुए सिचाई तथा पेयजल योजनाओं के लिये सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं।

हमारा संकल्पः अधिक विद्युत उत्पादन, बेहतर उपभोक्ता सेवा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन, १४, अशोक मार्ग, लखनऊ

KRITI/UPSEB/487

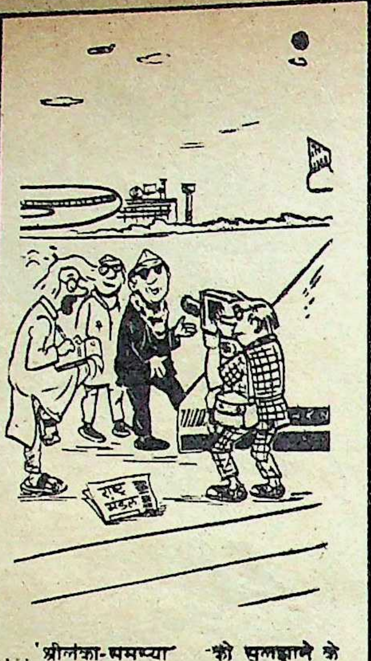

. . . 'श्रीलंका-समस्या' को सुलझाने के बाद अब हम 'फीजी' की समस्या का निपटारा करने जा रहे हैं!

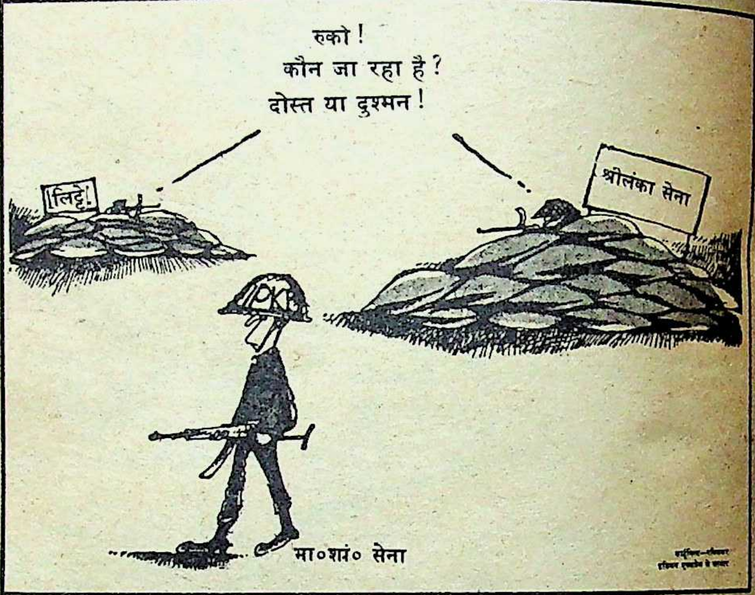
रुको!
कौन जा रहा है?
दोस्त या दुश्मन!
लिट्टे
श्रीलंका सेना
IPKF
भा०शां० सेना

कार्टूनिस्ट—रविशंकर
इंडियन एक्सप्रेस के साभार

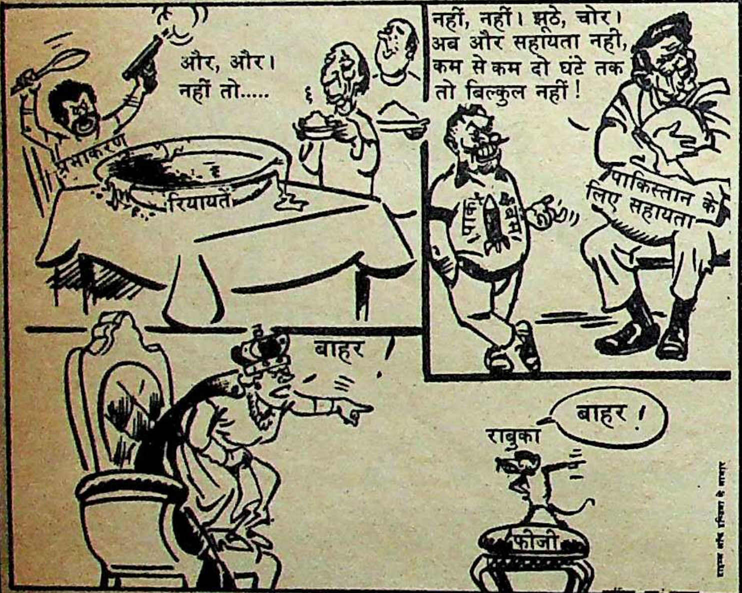
और, और। नहीं तो.....
प्रभाकरण
रियायतें
नहीं, नहीं। झूठे, चोर। अब और सहायता नही, कम से कम दो घंटे तक तो बिल्कुल नहीं!
पाकिस्तान के लिए सहायता
बाहर!
राबुका
बाहर!
फीजी

टाइम्स ऑफ इंडिया के साभार

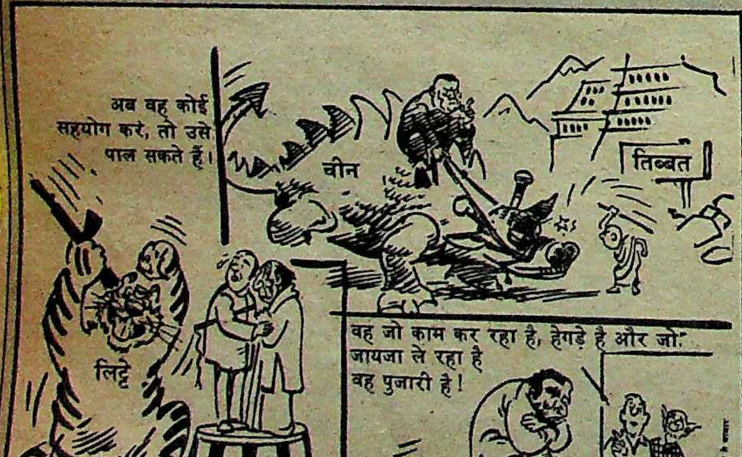
अब वह कोई सहयोग करे, तो उसे पाल सकते हैं।
चीन
तिब्बत
लिट्टे
समझौता
वह जो काम कर रहा है, हेगड़े है और जो जायजा ले रहा है वह पुजारी है!
सूखा सहायता

टाइम्स ऑफ इंडिया के साभार

कार्टूनिस्ट: आर० लक्ष्मण

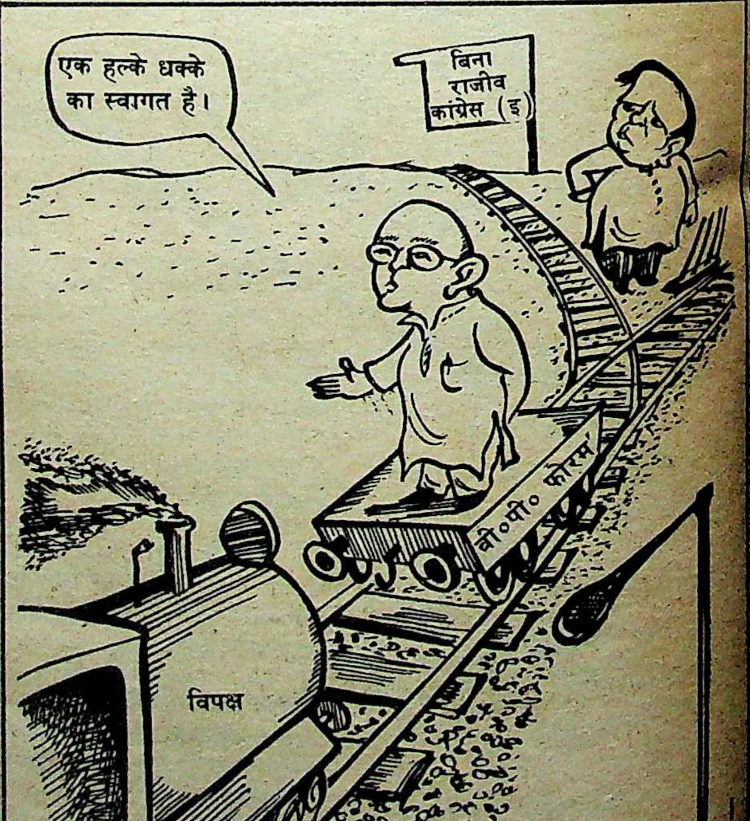
एक हल्के धक्के का स्वागत है।
बिना राजीव कांग्रेस (इ)
वी०पी० फोरम
विपक्ष

अगर आपको ये वाकिया बढ़ाया-चढ़ाया सा लगे...

तो शायद आपने अब तक 'फ्रेंची' पहना ही नहीं!

वी आइ पी फ्रेंची. छोटा-सा बढ़िया जांघिया... चुस्त-दुरुस्त
और मर्दाना ताकत से सराबोर. सारी दुनिया में इसकी
मर्दानगी ने तहलका मचा रखा है और हमारे शहरों में भी
इसी की धाक है, बोलबाला है! सचमुच एक ऐसी
अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल, एक ऐसा अंदाज़ जो वी आइ पी
लाये हैं ख़ास आपके लिए!

VIP
फ्रेंची
जांबाज़ मर्दों के मनपसंद

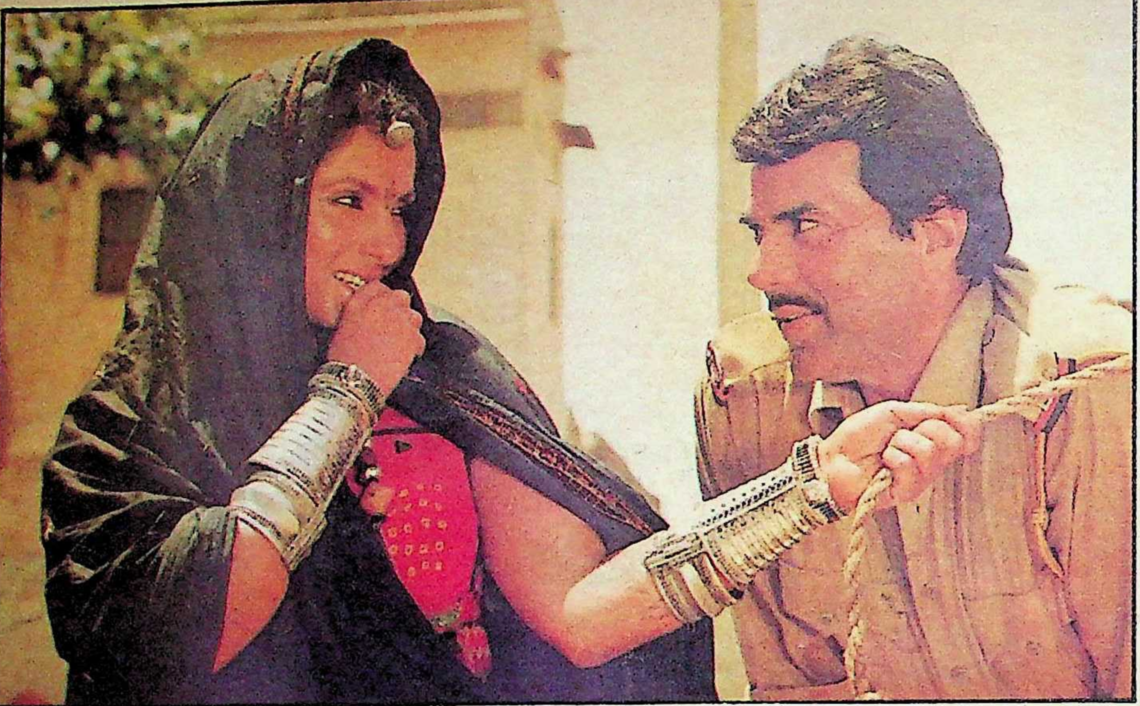

डिंपल कापड़िया और धर्मेंद्र फिल्म 'बंटवारा' में

एक म्यान, दो तलवारें

सन्नी देवल अभी भी डिंपल को भुला नहीं पाया है जबकि डिंपल के लिए सन्नी अतीत का अध्याय बन चुका है। "सन्नी के साथ अब और कोई फिल्म नहीं" का निर्णय लेने में डिंपल ने भले ही देर लगाया हो, लेकिन सन्नी के पापा धरम (धर्मेंद्र) के साथ 'बंटवारा' में नायिका की भूमिका निभाने में उसने एक क्षण का भी विलम्ब नहीं किया। बल्कि 'बंटवारा' की जिस भूमिका को श्रीदेवी, रेखा और जयाप्रदा सारे जोड़तोड़ के बावजूद हथिया नहीं सकी थीं, उसे डिंपल ने खुद भाग-दौड़ कर हासिल कर लिया। वह भी उस खुर्राट निर्देशक जे०पी० दत्ता से जिसके साथ वह फिल्म 'गुलामी' और 'हत्यारे' नहीं कर सकी थी। नंबर-वन स्टारडम की तरफ तेजी से बढ़ रही डिंपल को भुला पाने में असफल सन्नी 'बंटवारा' की शूटिंग के दौरान जयपुर जा पहुंचा। उसे पता था कि शुरू के कुछ दिनों में पापा धरम की शूटिंग नहीं होने के कारण वह जयपुर नहीं होंगे। धर्म संकट में फंसी पापा की हीरोइन डिंपल गाय की तरह सन्नी के पीछे-पीछे चली गयी, लेकिन जे०पी० दत्ता का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचे कि इस संकट से धरम ने सभी को उबार लिया और एक लंबा-चौड़ा हरियाणवी स्पीच थमाकर सन्नी को बैरंग बंबई भेज दिया।

अब कौन सन्नी को समझाये कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे अंट सकती हैं।

फर्क अर्चना-अर्चना का!

'जलवा' ने माडल-से-हीरोइन अर्चना पूरन सिंह के ग्लैमर का जलवा कुछ इस तरह बरपा किया कि 'संसार'-'अमृता'-'चुनौती' वाली अर्चना जोगलेकर के लिए मुसीबत पैदा कर दी। 'चुनौती' टी०वी० सीरियल में चुलबुली पत्रकार और 'अमृता' टी०वी० सीरियल में शोख दुल्हन की भूमिका अर्चना जोगलेकर ने क्या निभायी कि अर्चना पूरन सिंह के लिए सिरदर्द हो गयी। अर्चनाओं के चक्कर में हैरान निर्माता ग्लैमरस भूमिका का अनुबंध-पत्र लेकर अर्चना जोगलेकर के पास जा पहुंचते हैं और शोख-चुलबुली लड़की की गंभीर भूमिकाओं का आफर अर्चना पूरन सिंह को दे बैठते हैं। दोनों की इन समस्याओं से प्रभावित और उद्विग्न हो एक फिल्म निर्माता ने दोनों को लेकर 'सीता बन गयी गीता' बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय स्त्री की इमेज को निभाने के लिए बेकरार अर्चना जोगलेकर की समस्या का यहीं अंत नहीं हुआ और न ही 'परफेक्ट मर्डर' की हीरोइन अर्चना पूरन सिंह का। अर्चना पूरन सिंह फिल्मों में जीनत-परवीन बाबी की जगह भरना चाहती है और अर्चना जोगलेकर, रेखा या श्रीदेवी का स्थान पाना चाहती है। अर्चना पूरन सिंह को कम परिधान पहनने में हिचक

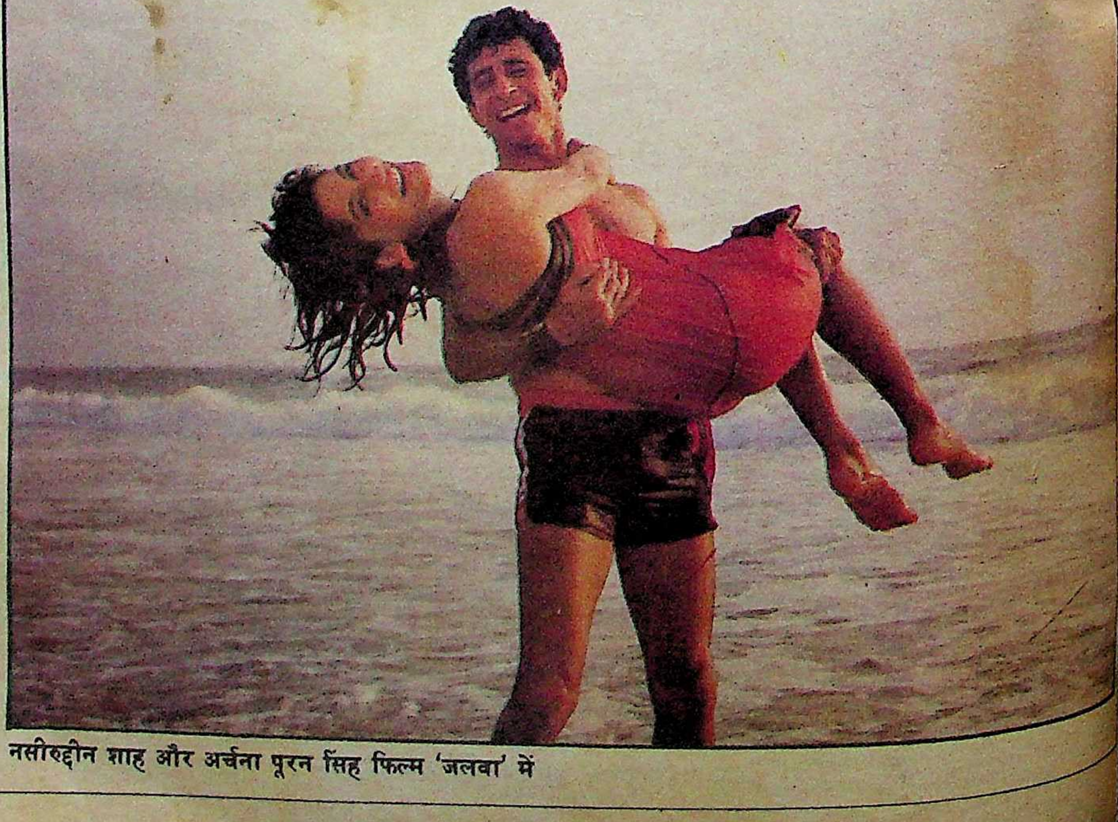

नसीरुद्दीन शाह और अर्चना पूरन सिंह फिल्म 'जलवा' में

अर्चना जोगलेकर छाया : महेश जॉली

नहीं और अर्चना जोगलेकर को पूरे परिधान चाहिए। अर्चनाओं की इस गलतफहमी में फंसे पटकथा-लेखक भी एक-दूसरे के लिए गलत रोल लिख बैठते हैं। लोगों ने दोनों को नाम का पहला शब्द 'अर्चना' बदल देने का सुझाव दिया तो वे बिफर पड़ीं—"क्या जोगलेकर और पूरन सिंह से फर्क नहीं लगता।"

सवाल है, दोनों की समस्या सुलझे तो भला कैसे। कुछ आप ही सुझायें उन्हें!

लता मंगेशकर की 'लेकिन'

पार्श्व गायन की दुनिया से धीरे-धीरे किनारा कस रहीं तथा विदेशों में गायन-यात्राओं में अधिक समय बिता रहीं लता मंगेशकर ने जब एक कहानी गुलजार से सुनी, तो उनकी आंखें भींग गयीं। कहानी सुनते समय उनके चेहरे पर परत-दर-परत बदलते भावों को गुलजार तो नहीं देख सके, लेकिन हिंदी फिल्मों की दुनिया में पांव जमाने में असफल उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने जरूर भांप लिया।

कुछ दिनों बाद एक अलस्सुबह गुलजार जब अपने बंगले 'बोस्कियाना' की बालकनी में खड़े दूर सागर की लहरें गिन रहे थे, पोटिको में एक खड़ी होती कार से उतरती महिला को देखकर नंगे पैरों भागते हुए नीचे आये, "अरे लता दीदी, आप?"

"उस दिन जो कहानी आपने सुनायी वह बाद में भी मुझे दिमागी तौर पर मथती रही। मैं इस पर फिल्म बनाना चाहती हूं। इसके लिए मैंने विनोद खन्ना, डिंपल और अमजद खान से बात भी कर ली है। वे पूरे डेट्स देने के लिए तैयार हैं। आपको अगर इन कलाकारों के बारे में आपत्ति नहीं हो तो..."

भला विनोद खन्ना को लेकर 'मेरे अपने,' 'अचानक' और 'मीरा' बनाने वाले गुलजार को क्या आपत्ति हो सकती थी? तुरत-फुरत फिल्म 'लेकिन' निर्माण की योजना बन गयी और मुहूर्त तथा शूटिंग की तारीख भी तय हो गयी। लताजी की ६०वीं सालगिरह (२८ सितंबर) पर इस फिल्म का काम भी शुरू हो गया।

लता मंगेशकर

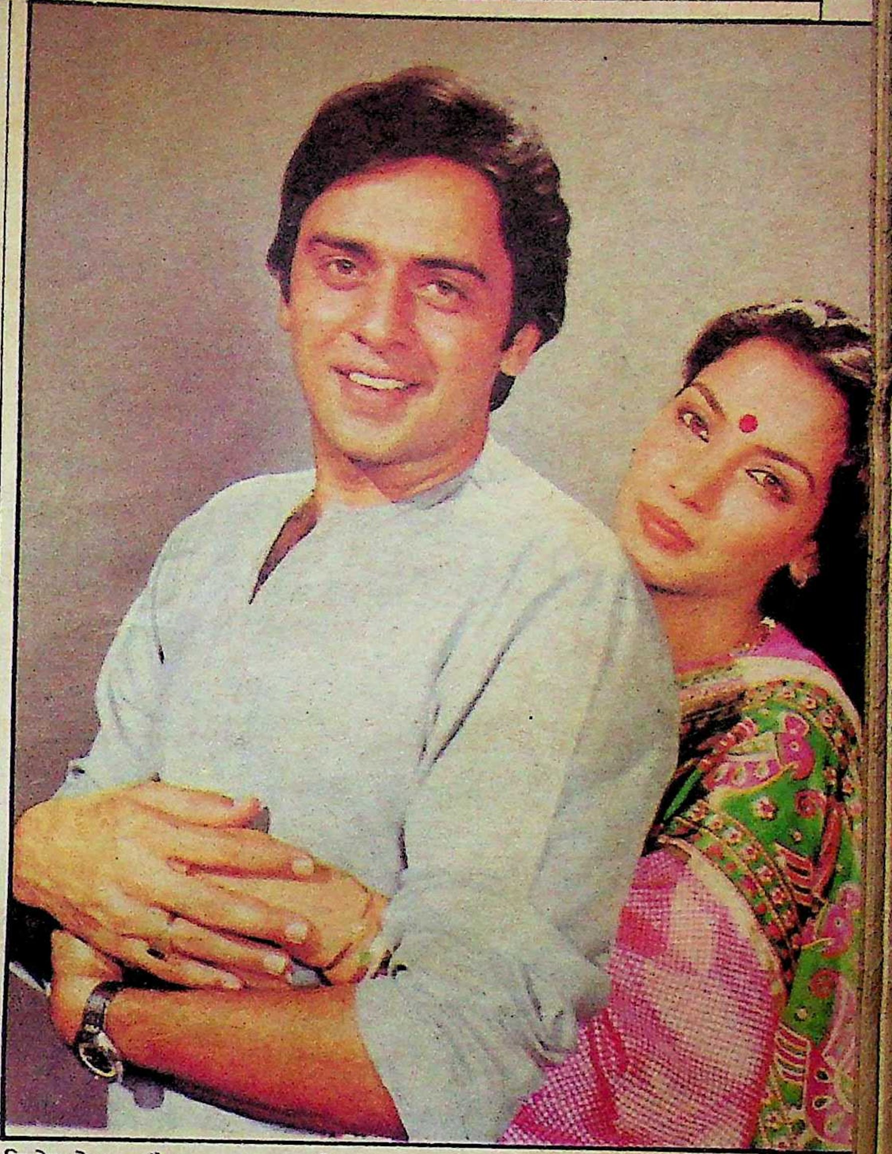

विनोद मेहरा और शबाना आजमी

शब्बो का सिग्नल!

जब से अपर्णा सेन ने शबाना आजमी का विवाह फिल्म 'सती' में एक पेड़ से सात फेरे लगाकर करवा दिया है, तबसे फिल्मी नायकों के बारे में शबाना का सोच बदल गया है। अब वह मानने लगी है कि कहानी और डायरेक्टर 'धांसू' हो, तो हीरो के रूप में पेड़ भी चल सकता है और विनोद मेहरा या मास्टर जोजो (कुत्ता) भी। इधर उसने लंबी नींद ले रहे अपने मियां जावेद अख्तर को झंझोर कर जगाना शुरू कर दिया है कि वह 'राम और श्याम' या 'सीता और गीता' जैसी स्क्रिप्ट अथवा 'दीवार' जैसी धांसू कहानी लिखें जिसमें हीरो की जगह हीरोइनवाली कहानी हो, एंग्री हीरोइन की। इससे समूची इंडस्ट्री में क्रांति आ जायेगी। सीता-गीता जैसी उस भूमिका(ओं) को शबाना बड़े धांसू ढंग से निभा कर समूचे नारी-जगत में जागरण पैदा कर सकती है और नारी प्रधान चरित्रोंवाली फिल्में लिखकर जावेद भी यश कमा सकते हैं। शायद शबाना और जावेद ने विषय भी सोच लिया है—जैसे झोपड़पट्टियां या फुटपाथ पर रहनेवालों के बीच हंटरवाली जैसी कोई धाकड़ औरत आकर पहले हंटर के जोर से फिर बप्पी लाहिड़ी की 'रम्बा हो हो' स्टाइल में उषा उथुप की आवाज में गाना गा-गा कर भू-स्वामियों का हृदय-परिवर्तन करा सकती है। या 'सीता और गीता' की गीता स्टाइल में या फिर 'गाइड' के देव आनंद की तरह अनशन कर दहेज लोभियों के सिर से दहेज का भूत उतार सकती है। विषय तो बहुत हैं और इन्हें बनाने के लिए डांसर-अभिनेता जोगिंदर सिंह भी तैयार हैं। उन्होंने फिल्म का नाम भी सोच लिया है 'जय मां शबाना की' या 'शब्बो हंटरवाली'। लेकिन शब्बो उर्फ शब्बी उर्फ शबाना किसको ग्रीन सिग्नल देंगी, यह तो वही बता सकती हैं। ●

मनोरमा

१५ नवम्बर' ८७

बुनाई विशेषांक

बुनाई विशेषज्ञों द्वारा तैयार नयनाभिराम नमूने पूरे परिवार के लिए

प्रमुख आकर्षण

- पुलोवर पर तैरती नाव
- चमकते सूर्य वाला पुलोवर
- नन्हे त्रिकोणवाला वनपीस पुलोवर
- नये नमूने का फ्रॉक कोट
- बेटे के लिए बुनिये बाबा सूट
- एक जैकेट किशोर-किशोरियों के लिए
- गोल गले का केबिलवाला पुलोवर
- मनमोहक हाईनेक पुलोवर
- बंद गले का पुलोवर
- कढ़ाई से सजा मनमोहक कार्डिगन
- एक सादा-सौम्य पुलोवर

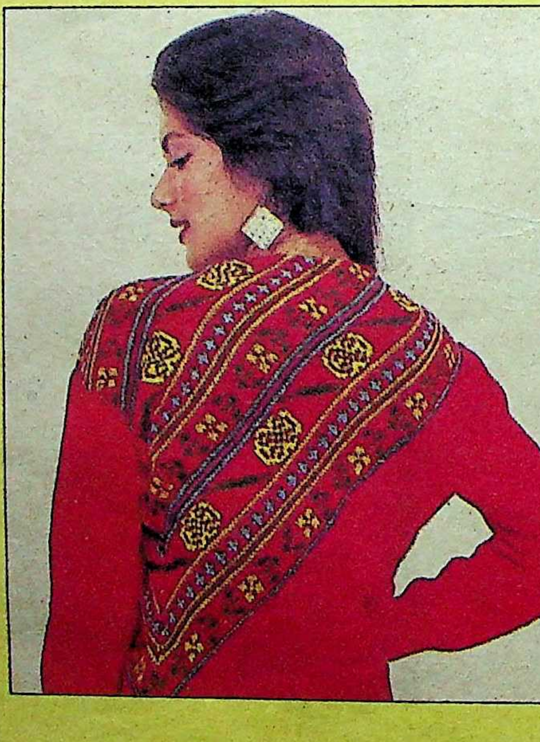

आवरण कथा :

जब प्यार की धड़कन धीमी पड़ने लगे

समझा यही जाता है कि पति-पत्नी जितने ज्यादा करीब आते जाएंगे, प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, प्यार भी चाहता है कुछ दूरियां। पढ़िए एक रोचक विवेचन।

अन्य आकर्षण :

- मेरी सुहागरात : 'बिजली की वह आंख-मिचौली'
- सौंदर्य : हाथों और नाखूनों की देखभाल
- व्यंजन : खस्ता पेस्ट्री : मीठी भी नमकीन भी
- फीचर : नेत्रहीनों और विकलांगों की कार रैली
- बच्चे और आप : क्या आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है ?
- दस्तकारी, कढ़ाई, फैशन, गृहसज्जा की लेटेस्ट डिजाइनें
- अनवर आगेवान की कहानी : 'नाथीबाई'
- सरोजनी प्रीतम की हास्य रचना : 'चाय-दर्शन'

नवम्बर प्रथम सप्ताह में प्रकाश्य

मूल्य-६.००

राजीव-मंत्रिमंडल में फेरबदल

३२ महीनों में २३ बार

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गत ३२ महीनों में २३ बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और ७९ सांसदों को मंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन कोई मंत्री औसतन छह से आठ मास से अधिक अपने पद पर नहीं रहा। मंत्रालय किस तरह चकरघिन्नी की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ घूमते रहे, इसकी एक बानगी है—विदेश मंत्रालय। यह मंत्रालय प्रथम नौ महीनों तक राजीव गांधी के पास रहा, फिर बलीराम भगत विदेश मंत्री बने, लेकिन सात महीनों में ही न केवल उनसे विदेश मंत्रालय ले लिया गया, बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल से ही बाहर फेंक दिया गया। फिर मई, १९८६ में पी० शिव शंकर विदेश मंत्री बनाये गये लेकिन पांच महीनों में ही यह विभाग उनसे छीनकर अक्तूबर, १९८६ में नारायण दत्त तिवारी को दे दिया गया, लेकिन दस महीनों के अंदर ही अर्थात २५ जुलाई, १९८७ को यह मंत्रालय उनके हाथ से निकलकर फिर राजीव गांधी के हाथों में चला गया।

भारत सरकार १९५१ से जनसंख्या नियंत्रण के लिए छेड़े गये अभियान के तहत ३६ वर्षों में अभी तक २४ अरब रुपए खर्च कर चुकी है और उसका दावा है कि इतना धन खर्च करके उसने ७ करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। इस प्रकार एक बच्चे को जन्म लेने से रोकने में सरकार को औसतन ३४० रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन जो बच्चा जनसंख्या नियंत्रण को धता बताकर पैदा हो जाता है, वह पैदा होते ही औसतन २६०.५० रुपए का विदेशों का कर्जदार हो जाता है (यह १९८३ का आंकड़ा है—अब तो यह राशि और भी बढ़ गयी है) जिस पर उसे प्रतिमास ८ रुपए ६० पैसे ब्याज के भी चुकाने हैं। भारत पर एक खरब, ८७ अरब, ४७ करोड़, ३० लाख रुपयों का विदेशी कर्ज है।

तीसरी दुनिया के मुल्क अर्थात रूस और अमरीका को छोड़कर भारत सहित शेष देशों पर १०८५ खरब डालर का विदेशी कर्ज है। अधिकांश कर्जदार दक्षिणी अमरीका, एशिया और अफ्रीका के मुल्क हैं। इन देशों ने पिछले दस वर्षों (१९७६-८५) में कर्ज के इस धन से अकेले अमरीका और पश्चिम यूरोपीय देशों से ३० खरब डालर के हथियार खरीदे। अर्थात इतना धन घूम-फिर कर इन्हीं कर्ज देने वाले मुल्कों के पास पहुंच गया। इन मुल्कों के पास पहुंचे हथियार इन मुल्कों के लोगों को पड़ोसियों से छिड़ी लड़ाइयों में मारने के काम में इस्तेमाल किये गये और किये जा रहे हैं। अनेक देशों के सत्ता केंद्र से जुड़े लोग मोटी दलाली देकर बिलावजह भी रक्षा-सौदे कर रहे हैं और दलाली में मिला धन स्विस एवं अन्य देशों के बैंकों में जमा करा रहे हैं। विश्व मुद्रा कोष के एक आकलन के अनुसार तीसरी दुनिया के मुल्कों से प्रतिवर्ष ३०० अरब रुपए स्विस बैंकों में पहुंचते हैं। मैक्सिको, अर्जेंटिना, वेनेजुयेला जैसे अनेक देशों की सरकारें इन दलालों के कारण दीवालिया भी हो चुकी हैं।

हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का नाम भी अब रोशन होने लगा है। १९८४ में हथियार खरीदनेवाले १५१ देशों में जहां भारत का ऊपर से दसवां स्थान था, वहीं १९८५ में वह तीसरे नंबर पर पहुंच गया। सऊदी अरब का स्थान पहला और इराक का दूसरा है, भारत ने १९८४ में करीब ११ अरब, २० करोड़ रुपए के हथियार खरीदे थे और १९८५ में उसने करीब ३६ अरब, ६० करोड़ रुपए के हथियार खरीदे। हथियारों पर बढ़े खर्च का एक बड़ा कारण यह बताया जाता है—रक्षा सौदे में सम्बद्ध भारतीय नेताओं और बिचौलियों को मिलनेवाली दलाली और यह दलाली गुपचुप स्विस बैंकों में जमा करा दी जाती है। स्विस बैंकों में बकौल भूतपूर्व रक्षा मंत्री वी०पी० सिंह भारतीयों ने अवैध रूप से १३ अरब रुपए जमा करा रखे हैं।

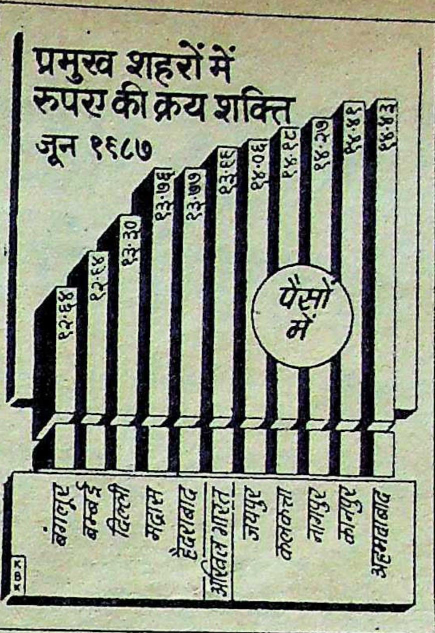

एक सरकारी अनुमान के अनुसार विदेशों से १९८५ में भारत के ३६१२ संस्थानों व व्यक्तियों को जहां २५३.८९ करोड़ रुपए दान के रूप में प्राप्त हुए थे, वहीं यह दानराशि १९८६ में बढ़कर ४३४.१८ करोड़ रुपए और दान लेनेवाले संस्थानों और व्यक्तियों की संख्या बढ़कर १००४१ हो गयी। संसद के गत सत्र में सांसदों ने दान के रूप में आने वाली इस धनराशि पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि जनकल्याण के नाम पर आयी इस धनराशि का दुरुपयोग भारत-विरोधी कार्यवाहियों के लिए किया जाता है।

देश सूखे और बाढ़ की वजह से अकाल के कगार पर खड़ा है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने १९८६-८७ में खाद्यान्न के रखरखाव और उसके परिवहन में ऐसी लापरवाही बरती कि ४ अरब रुपए के मूल्य का १८.५ लाख टन अनाज नष्ट हो गया। यह तो हर साल का सिलसिला है। भारत सरकार ने १९८४-८५ में भारतीय खाद्य निगम को सहायता राशि के रूप में जहां ११ अरब रुपए दिये थे, वहीं १९८६-८७ के लिए उसे २० अरब रुपए देने पड़े हैं। सूखा और बाढ़ न भी हो, तो भी जनता से ही इस नुकसान की भरपायी करने के लिए स्वयं सरकार ही अनाजों की मूल्य वृद्धि का कारण बन जाती है।

भारत में प्रति वर्ष १५ हजार लोग आग लगने की दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, तो ३० हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ देते हैं।

उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में सबसे कड़ी और बड़ी सजा मिली है सिवनी (मध्य प्रदेश) के थोक उपभोक्ता स्टोर (होल सेल कंज्यूमर स्टोर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। जिला सेशन जज ने उसे २४ वर्ष बामशक्कत जेल और ६० हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। उसके तीन महायकों और १२ विक्रेताओं को भी कड़ी सजाएं हुई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ दंगों से पीड़ित २३०० व्यक्तियों को ९८ लाख, ७४ हजार रुपए का मुआवजा दिया। इसमें ८३ मृतकों के लिए १६ लाख, ६० हजार, ९६ घायलों को ५३ हजार और शेष लोगों को सम्पत्ति-रक्षा के लिए ८१ लाख, ६१ हजार, ३ सौ रुपए का मुआवजा मिला।

देश के १७ राज्यों (आंध्र, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश) ने चालू वर्ष के बजट में १२ अरब रुपए का घाटा दिखाया है। केवल मणिपुर ही ऐसा राज्य है, जिसने एक करोड़ १४ लाख रुपए का लाभ होने का अनुमान किया है। प० बंगाल और जम्मू-कश्मीर ही ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें कोई घाटा नहीं होगा। घाटे को पूरा करने के लिए आंध्र, बिहार हरियाणा, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों ने ८ अरब, ३२ करोड़, १८ लाख के कर जनता पर लगाये हैं, जबकि २० राज्यों ने जनता से १५ अरब, ३४ करोड़, ७५ लाख रुपए के कर्ज मांगे हैं। सबसे ज्यादा कर्ज उत्तर प्रदेश ने (२ अरब, ८६ करोड़, २५ लाख रुपए) और सबसे कम कर्ज मणिपुर ने (१७ करोड़, २५ लाख रुपए) मांगा है।

पूरे देश में १८३ महिलाएं विमान चालक हैं। ■

'आखिरी मुगल'

एक बहादुर शहंशाह के जख्मों की दास्तां

प्रख्यात निर्माता निर्देशक बी०आर० चोपड़ा तथा उनके पुत्र रवि चोपड़ा मंडी हाउस की राजनीति से आखिरकार उबर ही गये। 'महाभारत' पर फीचर फिल्म बनाने की उन्होंने जो धमकी दी थी उसे वापस लेकर श्री चोपड़ा ने मंडी हाउस को धर्मसंकट से उबार लिया। पूर्व-स्वीकृत ५२ एपीसोडों में से छह एपीसोडों की श्री चोपड़ा शूटिंग कर चुके थे कि मंडी हाउस का ग्रीन सिग्नल अचानक रेड सिग्नल में बदल गया और 'महाभारत' के लगे-लगाये सेट को उन्हें तोड़ देना पड़ा था और लाखों रुपए खर्च कर विशेष रूप से तैयार कराये गये कास्ट्यूम, आभूषणों, विग तथा हथियारों आदि को बक्सों में बंद कर गोदाम में पहुंचा दिया गया था कि जब फीचर फिल्म का निर्माण करेंगे तो इनको निकालेंगे।

मंडी हाउस ने अब इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि 'रामायण' के जनवरी, १९८८ में खतम होने पर उसी टाइम स्लाट में वे 'महाभारत' को ५२ एपीसोडों में टेलीकास्ट करेंगे। महाभारत कांड की आंच में हाथ जला बैठे मंडी हाउस ने रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ महीने पहले न केवल बी०आर० चोपड़ा के एक और सीरियल 'आखिरी मुगल' को मंजूरी दे दी, बल्कि आवश्यक एपीसोडों की शूटिंग होते ही अपने टेलीकास्ट-शिड्यूलिंग में परिवर्तन का संकेत भी शुरू में ही दे दिया। 'कालाजल' के निर्माता-निर्देशकों की सारी दौड़-धूप के बावजूद 'कालाजल' को एक्सटेंशन न देने का निर्णय देते हुए १ सितंबर, '८७ से टेलीकास्ट भी करा दिया। मंडी हाउस ने जुलाई में ही 'आखिरी मुगल' को टेलीकास्ट करने की पेशकश की थी। लेकिन दूध के जले चोपड़ा पिता-पुत्र हर काम अब अपने ढंग एवं शर्तों पर चाहते थे। इसलिए अचानक दरियादिल हो आये दूरदर्शन अधिकारियों की इस पेशकश को ठुकरा दिया और काम अपनी संतुष्टि की हद तक पूरा हो जाने पर ही टेलीकास्ट करने का निर्णय किया।

"'आखिरी मुगल' बनाना उतना आसान नहीं था, जितना लोग आमतौर पर सोच लेते हैं" बी०आर० चोपड़ा ने 'माया' को बतलाया, "इसके लिए आवश्यक शोध करना जरूरी था। बहादुर शाह जफर भारतीय इतिहास के उस संधि-बिंदु पर खड़े थे जिसके एक तरफ मुगलों की विराट सत्ता का भूतकाल था, तो दूसरी तरफ आंधी से भी तेज रफ्तार से बढ़ रहे अंग्रेजी साम्राज्य का खतरा था।"

बहादुर शाह जफर की भूमिका में अशोक कुमार

बी०आर० चोपड़ा के पुत्र तथा इस सीरियल के निर्माता रवि चोपड़ा का कहना था, "बहादुर शाह जफर हमारे इतिहास के एक ऐसे कीर्ति-स्तंभ हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध, भारत की आजादी का नेतृत्व किया और हथियार उठाया। आज जब देश में प्रांतीयता और सांप्रदायिक वैमनस्यता का जहर तेजी से घुल रहा है, लोकतंत्र और आजादी के सामने खतरा एवं राष्ट्रीय एकता के खंड-खंड हो जाने का संकट पैदा हो गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहादुर शाह जफर का चरित्र इ संकट से हमें उबारने में सफल होगा।"

'आखिरी मुगल' के लेखक बलिया-निवासी डा० राही मासूम रजा ने 'माया' को बतलाया, "अंग्रेजों की नीति थी—फूट डालो और राज्य करो। वे हिंदुओं से कहते—मुसलमान विदेशी हैं, इस देश में रहने का उनका अधिकार नहीं है और मुसलमानों कहते—हिंदू तुम्हें विदेशी मानकर तुम्हें घृ करते हैं, हेय समझते हैं। उनकी इस नीति के विरु बहादुर शाह जफर ने फतवा दिया कि मुसलमा विदेशी नहीं हैं। उनकी तमाम पीढ़ियां इ हिंदुस्तान में पैदा हुईं, और मर गयीं। वे इसी जमी की संतान हैं। मैंने बहादुर शाह जफर की इस दली को प्रभावशाली ढंग से पेश करने के लिए सीरिय में इस तरह के कई दृश्य डाले।"

बहादुर शाह जफर की भूमिका निभा दादा मुनि (अशोक कुमार) ने 'माया'

'आखिरी मुगल' का एक दृश्य

बतलाया, "अंग्रेज इतिहासकारों ने इस महान देशभक्त को कायर, दब्बू और असहाय शासक की संज्ञा दी थी। हमारे इतिहासकार भी इस तथ्य को नकारते रहे कि भारतीय आजादी का बीज-मंत्र फूंकनेवालों में बहादुर शाह जफर अगुवा थे। कब्र में पैर लटकाये जफर ने अंग्रेजों द्वारा फैलाये गये विद्वेष के जहर के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता पैदा करने की जो कोशिश की थी, उसी कारण प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में हर संप्रदाय-धर्म के लिए निहित पवित्र भावना से एकजुट हुए और शहीद होने से नहीं हिचकिचाये। उनके चरित्र को निभाने में जो सुकून मैंने हासिल किया है, वह पचास सिल्वर या गोल्डेन जुबली फिल्मों में काम करके भी नहीं पाया है।"

बी०आर० चोपड़ा ने इस सीरियल की पटकथा तैयार कराते समय ब्रिटिश इतिहासकारों पर ही निर्भर रहकर वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने की भी कोशिश की। उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वारा नवाबों-राजाओं को आपसी भेदभाव भुलाकर एकजुट होने के लिए जो पत्र लिखे थे, उन पर भी शोध करवा कर सामग्री एकत्र करवायी।

सीरियल की शुरुआत ६२ वर्ष की उम्र में बहादुर शाह जफर की ताजपोशी से शुरू होती है। उन्हें अपने महान पूर्वजों (बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां) की—उनकी सत्ता और महानता की याद आती है,तो अपनी विवशता का कड़वा अहसास भी होता है। सीरियल का समापन उनकी मौत के साथ होता है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण अंश हैं, वे अदालती दृश्य जिनमें नजरबंद बहादुर शाह जफर को अवमाननाओं के दंश उठाने पड़ते हैं, महल में बेगमों, राजकुमारों की साजिशों-ऐयाशियों के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। एक जगह वह कहते हैं—'अधिकार की बात कहते हो? मैं तो एक मामूली कोतवाल से भी गया-बीता हूं।'

बहादुर शाह जफर की भूमिका निभाने के लिए बी०आर० चोपड़ा के सामने कई नाम थे—अशोक कुमार, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर आदि जाने-माने सितारे, लेकिन उन्होंने अशोक कुमार को ही चुना।

—रवीन्द्र श्रीवास्तव

(अशोक कुमार)और जीनत महल (नाजनीन)

साक्षात्कार/**बी०आर० चोपड़ा**

कोई विवाद नहीं है हमारे बीच

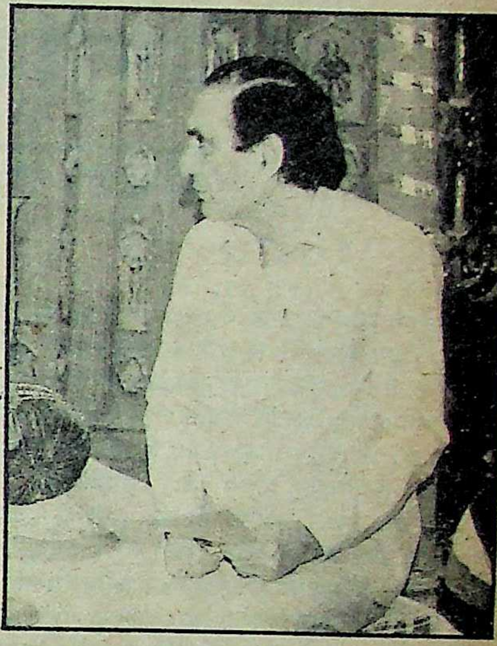

माया: तो आपके और मंडी हाउस के बीच विवाद का अंत हो ही गया...?

बी०आर० चोपड़ा: (हंसकर) कोई विवाद नहीं है हमारे बीच। बेकार ही बात का बतंगड़ बन गया। १ सितंबर से तो आप सभी लोग 'आखिरी मुगल' को देख ही रहे हैं। 'महाभारत' भी जल्दी ही देख लेंगे।

माया: 'महाभारत' पर तो आपने काफी अध्ययन किया था, बहादुरशाह जफर के बारे में क्या रहा?

चोपड़ा: उनसे संबंधित अधिक ग्रंथों-दस्तावेजों का हमने अध्ययन किया है। हमने ही नहीं, इस सीरियल के निर्माण से संबंधित हर किसी ने इस पर काफी काम किया—उस समय की घटनाओं से लेकर बाद की स्थिति तक का। यह संभव नहीं है कि हम उस समय के हालात और तात्कालिक परिवेश को हूबहू प्रस्तुत करें। हमने अपने हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन भी किये हैं, जिससे युवकों को प्रेरणा भी मिल सके।

माया: क्या आप चौदह एपीसोडों में जफर का जीवन-चरित्र बांध सकेंगे?

चोपड़ा: ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक बादशाह के जीवन को मात्र आधा घंटे के एपीसोड के माध्यम से उसे हम पूरा बांध सकें। इसके लिए हमने बहादुर शाह जफर की ताजपोशी के दृश्य से सीरियल की शुरुआत की है। इजाजत तो तेरह की मिली थी, लेकिन उसके बाद एक और एपीसोड बढ़ा दिया गया। इसीलिए हमने ताजपोशी से मृत्यु तक के बीच का भाग दिखाया है।

माया: क्या पात्रों के काम से संतुष्टि है आपको?

चोपड़ा: यह तो हम क्या, दर्शक ही बतायेंगें कि हमारे पात्र किस तरह से अपनी-अपनी भूमिकाओं में फिट बैठे हैं। सभी ने बहुत मेहनत की है और उर्दू बोलने का भी बहुत अभ्यास किया है। जहां तक बहादुर शाह जफर की भूमिका का सवाल है, मैं समझता हूं दादा मुनि (अशोक कुमार) के अलावा कोई दूसरा इतनी खूबी से नहीं निभा पाता। जब उन्हें यह भूमिका सौंपी गयी तो वह बेहद खुश हुए और उन्होंने बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार कर लिया। शेष अन्य पात्र, जैसे—बहादुर शाह की बेगम—जीनतमहल (नाजनीन), एहसानउल्ला खां (रूपेश कुमार), शहजादा मुगल (अरुण बख्शी), पीर जमाल (जान्हवी), जिसका इश्क शहजादे के साथ है, मौलवी (राममोहन), अकबर (राज बब्बर), नूरजहां (जूही चावला), कर्नल हडसन (मि० एडीतार मास्टर), शहजादा (मयूर), मिर्जा गालिब (शफी इनामदार), रेजिडेंट मेटकाफ (गुफी पेंटल) के अलावा पेंटल, रफीक मुकादम आदि ने प्रभावशाली भूमिकाएं निभाकर उन चरित्रों में जान डाल दिया है।

माया: सीरियल के कुछ प्रभावशाली प्रसंगों के बारे में बतलायेंगे?

चोपड़ा: बहादुर शाह के दो बेटों का कत्लकर हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह को प्रजेंट दिया जाता है। यह कारनामा कर्नल हडसन के आदेश पर हुआ था। ऐसे दृश्यों ने 'आखिरी मुगल' में जान डाल दी है।

माया: हम थोड़ा 'महाभारत' सीरियल के बारे में भी बात कर लें। इससे पहले आपने 'महाभारत' सीरियल शुरू किया था, लेकिन बीच में ही उसका निर्माण रोककर 'आखिरी मुगल' क्यों बनाने लगे, उसे क्यों नहीं पहले पूरा किया?

चोपड़ा: देश के वर्तमान हालात को देखते हुए यह सीरियल ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए इसका निर्माण पहले किया।

माया: लेकिन कहा तो यह जाता है कि 'रामायण' की वजह से घबड़ा कर आपने उसका निर्माण रोक दिया।

चोपड़ा: ऐसी बात नहीं है। 'महाभारत' रामायण से भी पुख्ता एवं प्रभावशाली कथा है। किसी की स्पर्धा से हमने घबड़ा कर ऐसा नहीं किया।

—महादेव शर्मा

क्या राजीव गांधी अपनी आर्थिक नीति बदल रहे हैं ?

कुछ समाचार पत्रों ने उदारीकरण की नीति में नये परिवर्तनों के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। उदारीकरण का अर्थ चाहे जो हो पर कुछ समय से, यहां तक कि राजीव गांधी के सत्ता में आने के पूर्व भी यह एक फैशन-सा हो गया था। किंतु उनके (राजीव गांधी के) शासन को तो 'उदारीकरण का शासन' ही कहा जाता है। इसके लिए उन्हें देश के अनेक लोगों की वाहवाही भी मिली। बुद्धिजीवियों, विशेषकर अर्थशास्त्रियों के एक समूह और समूचे व्यावसायिक समुदाय ने उदारीकरण के पक्ष में परिवर्तन का स्वागत जोरशोर से यह कहकर किया था कि केवल इसी से देश और जनता का भविष्य बनाया जा सकता है। किसी ऐरे-गैरे ने नहीं, खुद अमरीकी राष्ट्रपति रेगन ने १९८५ में कहा था कि राजीव गांधी अपनी नयी नीति से चमत्कार कर रहे हैं।

किंतु अचानक उदारीकरण की नीति बदलने लगी है। सरकार एक ऐसी छवि पेश करने के लिए प्रयासरत है, जिसे इस देश में समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। ताजा मिसाल नये करों की शृंखला है, जिसे गत सितंबर के मध्य में लागू किया गया। ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं, जिन्हें केवल धनी और उच्च मध्य वर्ग अदा करता है। निजी आय, व्यावसायिक आय, धन-संपत्ति और ऐसी अन्य वस्तुओं पर कर। प्रथम और उच्च श्रेणियों के रेल किराये तथा विमान किरायों में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिन लोगों की आमदनी ५० हजार रु० से अधिक है, उन पर आयकर इस वर्ष बढ़ा दिया गया है। ५ प्रतिशत का अतिरिक्त अधिशुल्क जोड़ दिया गया है और आयकर दाताओं से अतिरिक्त कर का एक भाग सितंबर के अंत में जमा करने को कहा गया।

करों में उदारता क्यों? : राजीव गांधी

इस सब का संबंध धनी और संपन्न लोगों से है। कुछ सरकारी प्रवक्ताओं ने इसे एक मिसाल के रूप में प्रचारित किया है कि सरकार धनियों पर कर लगाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि वह चाहेंगे कि जो समर्थ हैं उन्हीं पर नये करों की अदायगी का भार हो। इससे महत्वपूर्ण यह है कि कराधान के इस नये कदम से सरकार खुद अपने वायदों से पीछे हटी है। इसने गत वर्ष लंबी अवधि की एक प्रत्यक्ष कर नीति की घोषणा की थी तथा तत्कालीन वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा था कि प्रत्यक्ष करों में कम-से-कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह वायदा झूठा साबित हुआ है, किंतु किसी ने इसके विरोध में अधिक मुंह नहीं खोला। इसकी वजह है अर्थ व्यवस्था के लिए आपातकाल जैसी स्थिति का होना। इस आपातकाल का जनक है अभूतपूर्व सूखा। भुखमरी के शिकार, फसल और मवेर्शी गंवाने वाले और मुख्यतः खेती बाड़ी के कामकाज से रोजाना की रोटी कमाने वाले मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन की उगाही आवश्यक है। इसलिए कोई भी नये करों के औचित्य पर खुलकर सवाल नहीं कर मकता। इसके अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कुछ धनी लोग और उनके समर्थक राजीव गांधी से नाखुश हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी (धनिकों की) परवाह तब की जाती है, जब सरकार सरलतापूर्वक काम करती है, जब सरकार की स्थिरता या सत्ताधारी लोगों को कोई खतरा नहीं होता। जब यह खतरा गंभीर और उजागर हो जाता है, तो प्रधानमंत्री से लेकर उनके अदने सलाहकार तक, सब दिखावटी दावे करते हैं। ऐसे दावे कि उनकी सरकार केवल गरीबों की, गरीबों के लिए और गरीबों द्वारा संचालित है। क्योंकि यही एकमात्र तरीका है, जिससे आम लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि उन्हीं के हितों की रक्षा उनके नेता द्वारा की जा रही है।

अनिश्चितता का काल: पिछले कुछ महीने प्रधानमंत्री के लिए लगभग पूर्णतया अनिश्चितता का काल रहा है। भ्रष्टाचार की एक-के-बाद एक कथाओं और इसके साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह के रहस्योद्घाटनों ने राजीव गांधी को जनता से सीधा संपर्क जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जनता के बारे में सोचते हुए हमें याद रखना चाहिए कि बहुसंख्य लोग वे हैं जो टेलीविजन, वीडियो और नहाने के महंगे साबुनों की बात तो दरकिनार बड़ी फैक्ट्रियों में बनी वस्तुओं तक का प्रयोग नहीं करते। उनके लिए तकनीकी प्रगति का कोई अर्थ नहीं, जब तक कि ऐसी प्रगति उन्हें प्रकट और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करे। तकनीकी प्रगति, उद्योग व कृषि की उच्चतर उत्पादकता अथवा २१वीं शताब्दी की ओर तेज रफ्तार से बढ़ने की लुभावनी बातों से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं। दूसरी ओर जब विदेशी सहयोग को तकनीकी प्रगति के लिए सहजतापूर्वक उपलब्ध कराया जाता है, उद्योगपतियों को दोपहिया स्कूटर, कार (मसलन मारुति) कंप्यूटर या रंगीन टेलीविजन सेट्स बनाने के लिए तरह-तरह की रियायतें दी जाती हैं, तो आम आदमी सोचता है कि सरकार ऐसे सामान के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है, जो गरीब आदमी की पहुंच के बाहर है।

इस प्रक्रिया में कुछ लोग, जो समझदार हैं, सरकार की अपनी आर्थिक नीति में धनी वर्ग के प्रति झुकाव की बातें करने लगते हैं। यह प्रवृत्ति पहले भी थी, किंतु वर्तमान सरकार की उदारीकरण की नीति की अनेक लोग कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि आजादी के बाद से धनी-समर्थक ऐसा रुख पहले कभी नहीं था। इन लोगों के पास ठोस तर्क हैं। राजीव सरकार का धनी और संपन्न वर्ग के प्रति पक्षपात का सबसे बड़ा उदाहरण है करों के मामलों में अनंत उदारता। करदाता व्यक्ति लाभान्वित हुआ है—कम-से-कम कर अदायगी की रकम के मामले में। साथ ही, पहले बहुतेरे जो थोड़ा-बहुत आयकर देते थे उन्हें इससे छूट दी गयी। ये कौन लोग हैं? इनकी तादाद ३५ लाख लोगों से अधिक नहीं। यह उन भारतीयों की कुल संख्या का एक अंश मात्र है जौ नौकरी या संपत्ति से धनार्जन करते हैं। ऐसे लोग दो प्रतिशत से भी कम हैं।

लाड़ला वर्ग: व्यवसायी वर्ग बहरहाल वर्तमान सरकार का लाड़ला रहा है। करों के रूप में उन्हें अनेक रियायतें गत ढाई वर्षों में प्रदान की गयीं। कर और लेखा कानूनों में ऐसी अनेक नयी ढीलें दी गयीं, जिनसे व्यवसायी लोग अपने व्यवसाय में बढ़ा-चढ़ा कर खर्च दिखा सकें और वास्तविक लाभ को कम दिखाकर आयकर कम-से-कम अदा कर सकें। निजी कंपनी को अनेक नये उत्पादों के लाइसेंस देने के मामले में पहले के नियंत्रणों को हटा

बों द्वारा
रीका है,
ा सके कि
ी जा रही

छ महीने
श्चितता
बाद एक
ा सिंह के
से सीधा
जनता के
हिए कि
यो और
नार बड़ी
हीं करते।
नहीं, जब
क्ष रूप से
ा व कृषि
ाब्दी की
ों से उन्हें
विदेशी
तापूर्वक
यों को
कंप्यूटर
ए तरह-
आदमी
ादन को
पहुंच के

ज्ञदार हैं,
र्ग के प्रति
पहले भी
की नीति
हते हैं कि
ख पहले
तर्क हैं।
ों के प्रति
क मामलों
भान्वित
रकम के
ड़ा-बहुत
ये कौन
से अधिक
एक अंश
करते हैं।

बहरहाल
ों के रूप
प्रदान की
नेक नयी
व्यवसाय
ास्तविक
कम अदा
त्पादों के
ों को हटा

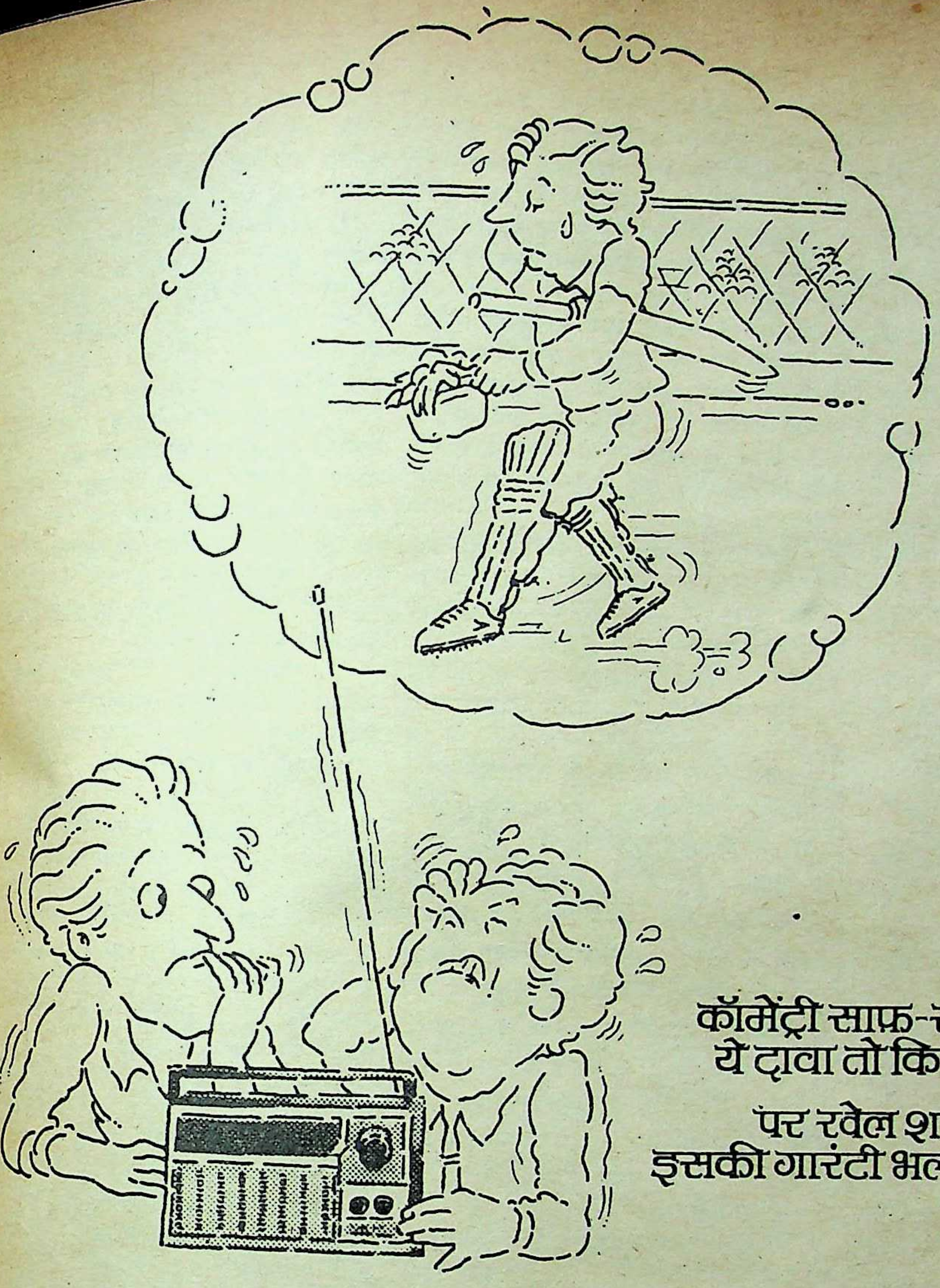

कॉमेंट्री साफ़-साफ़ सुनाई देगी,
ये दावा तो किया जा सकता है.

पर खेल शानदार होगा...
इसकी गारंटी भला कौन दे सकता है?

ये तो हो सकता है कि खेल में उतार-चढ़ाव आएं.
पर बैटरी में ऐसा हो... ये भला कैसे हो सकता है!
ये दावा है नोविनो का.
क्योंकि नोविनो क्वालिटी यानी लंबा सेवाकाल,
ज़्यादा शक्ति, अधिक रिसाव-प्रतिरोधकता जैसे शब्दों का
घिसा-पिटा इस्तेमाल नहीं बल्कि नोविनो क्वालिटी तो वो है
जिसका सुबूत आपको तब मिले जब आप इसे
खुद सुनें या खुद देखें!
नोविनो.
ऐसी बैटरी जो अपनी क्वालिटी का सुबूत खुद देती है—
बार-बार, लगातार!

NOVINO
HYPER
Leak Proof
National
LAKHANPAL
MADE I

National नोविनो

लखनपाल नेशनल लिमिटेड
बड़ौदा, गुजरात

नेशनल और पैनासोनिक उत्पादों के निर्माता
मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जापान
के साथ संयुक्त उपक्रम

ओह! नोविनो

Sista's-LNL-241/86 HN A

दिया गया। दूसरे उत्पादों के मामले में अधिक उदार लाइसेंस नीति अपनायी गयी। नतीजतन अनेक नयी कंपनियां बन गयीं। एक दृष्टि से यह अर्थतंत्र के लिए अच्छा है। नया पूंजीनिवेश होता है और निवेशकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। किंतु अपरिहार्य शीघ्र ही घटित होने लगा। बड़ी कंपनियों को एक उत्पाद के बाजार का अधिकांश भाग मिलने लगा और छोटी और मंझोली कंपनियां कठिन स्थिति का सामना करने लगीं। इसका कारण है एक उद्योग जितनी मात्रा में उत्पादन कर सकता है उतनी मांग नहीं है। इस प्रकार जिन बहुतेरे व्यवसायियों ने पूंजी लगायी थी, वे तेजी से बेकारी का शिकार होने लगे। उनकी मदद का एक तरीका था उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क घटाकर मांग बढ़ायी जाती। इससे उत्पादन लागत घटायी जा सकती और कपनी अपने उत्पाद सस्ते दर पर बेच पाती। किंतु इसका अर्थ क्या है? टेलीविजन सेटों या घरेलू रेफ्रिजरेटरों पर उत्पाद शुल्क घटाया जाये अथवा इन वस्तुओं के निर्माता जिन जिंसों को विदेशों से खरीदते हैं, उनका आयात शुल्क घटाया जाये। लेकिन इस प्रकार उत्पादन लागत और मूल्य में कमी होने की प्रक्रिया में लाभान्वित कौन होता है? इन सामानों को बनाने वाली कंपनी और खरीदार। दूसरे शब्दों में व्यवसायी, धनी और अपेक्षाकृत खुशहाल लोग। गरीब कतई नहीं।

गरीबों की शामत: दूसरी तरफ यदि जरूरी सामानों पर शुल्क नहीं घटाया जाता या बढ़ाया जाता है, तो ऐसे सामान का मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार गरीब आदमी सर्वाधिक प्रभावित होता है। मसलन यदि केरोसिन तेल महंगा होता है, तो गरीब आदमी सरकारी खजाने में दूसरों की अपेक्षा अतिरिक्त धन अदा करता है। क्योंकि यह एक जरूरी जिंस है और आदमी को रोटी और दालें पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करना लाजिमी है। जिसकी आय अधिक है, उसका केरोसिन (अथवा खाना पकाने की गैस, यदि उसका दाम बढ़ा है) के लिए अतिरिक्त खर्च उसके मासिक बजट का बहुत छोटा भाग होगा। पर गरीब आदमी पर यह लागू नहीं होता।

आसान शब्दों में कहें, तो गरीब आदमी की वास्तविक आय से धनी या खाते-पीते आदमी की तुलना में अधिक कटौती होती है। एक अदृश्य तरीके से आय के बंटवारे में विभिन्न आय समूहों के बीच इस ढंग से परिवर्तन किया जाता है, जो गरीब के लिए गैरफायदेमंद होता है। इसी प्रकार लाइसेंस नीति (यह सरकारी नीति है कि किस सामान का कितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए) परोक्ष रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार कर नीति (किस प्रकार के सामान पर अधिक कर लगाना चाहिए और किस पर कर का बोझ डालना है) संचालित होती है। क्योंकि संपन्न वर्गों या व्यवसायियों को करों में दी जाने वाली हर रियायत का सीधा मतलब है कर का वह बोझ निम्न आय समूहों पर डालना। सरकार को रियायतों से जो हानि होती है, उसकी अधिकांश भरपाई वह दूसरों पर भारी कर लगाकर करती है।

किंतु धनी वर्ग के प्रति इन सब पक्षपातों के बावजूद एक ऐसी निश्चित सीमा है, जिससे अधिक कर गरीब से राजस्व की शक्ल में वसूला नहीं जा सकता क्योंकि गरीब की अदायगी की क्षमता नहीं रह जाती। इसलिए जब संयम की सीमा आ जाती है, तो सरकार को अन्य तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। अधिक नोट छापना (आम भाषा में 'घाटे की अर्थ व्यवस्था') एक तरीका है। पर्याप्त बचत वाले लोगों से सरकार का उधार लेना दूसरा तरीका है। धनियों पर कर लगाना तीसरा विकल्प है। चौथा है ऐसे सामान और सेवाओं का मूल्य बढ़ाना, जिनकी बिक्री सरकार करती है। रेल, डाक, कोयला या बिजली आदि ऐसे सामान और सेवाएं हैं। घाटे में कमी का एक तरीका यह भी है—खर्चों में कटौती करना।

सरकार ने अंतिम तीन तरीकों को अपनाना पसंद किया है। प्रत्यक्ष कर बढ़ा दिये गये। रेल और विमान किरायों में वृद्धि कर दी गयी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार के खर्च में ५५० करोड़ की कटौती करने का फैसला किया जा चुका है। ऐसे कदमों से ११०० करोड़ रु० के अतिरिक्त खर्च के वहन की संभावना है।

> *इसकी क्या गारंटी कि अधिसंख्य कांग्रेस संसद सदस्य, यह अनुभव होने पर कि राजीव गांधी आम चुनाव के विकट संघर्ष में उनके रक्षा कवच सिद्ध नहीं होंगे, अपने नेता का साथ नहीं छोड़ेंगे? हर स्थिति में सामान्य आम चुनाव में केवल २७ महीने बाकी हैं। छवि रातों-रात बन-संवर नहीं सकती। इसमें वक्त लगता है।*

किंतु उल्लेखनीय बात यह है कि निम्न आय समूहों पर सीधा सरकारी राजस्व का बोझ बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसे ही 'उदारीकरण' की नीति को तिलांजलि देने के रूप में देखा जा रहा है। यह एक माह पूर्व हुई कुछ अन्य घटनाओं की पृष्ठभूमि में उजागर हुआ है। कांग्रेस समाजवादी फोरम को कई वर्षों बाद पुनर्गठित किया गया है। यह कांग्रेस-इ के अंदर का एक मंच है जो समाजवाद की बातें करता है और सुझाव देता है कि सरकार आर्थिक नीति के मामलों में क्या करे और क्या न करे।

फोरम ने अपने पुनर्गठन के फौरन बाद पूर्व वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर यह कह कर हमला किया कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाये गये समाजवाद के मार्ग को त्याग दिया था। जैसे तमाम नीतिगत मसले वित्तमंत्री स्वयं तय करते थे अथवा राजीव गांधी इन तमाम वर्षों में मात्र अपने वित्तमंत्री के निर्देश पर चलते थे। फोरम का कथन है कि सिंह के हटने से राजीव गांधी की सरकार समाजवाद का जामा पहन लेगी। धनी वर्ग का अब कतई पक्ष नहीं लिया जायेगा और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने केवल गरीबों की ही भलाई का फैसला किया है।

निस्संदेह एक दबाव भी दरपेश है—एक नया दबाव। पहले भी अर्थ व्यवस्था के भीतर 'उदारीकरण' की नीति की सीमाएं अनेक रूपों में मौजूद थीं। मसलन आप व्यवसायियों को पूंजी लगाने के लिए तब प्रेरित नहीं कर सकते, जब उन्हें ज्ञात हो कि जो उत्पादन वह करेंगे उसे बेच नहीं पायेंगे। भले ही आप प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय फर्मों से सहयोग के अनुबंध को आसान कर दें, पर वे सावधानी बरतेंगे। क्योंकि जिन लोगों के पास पहले से एक विशेष सामान के बाजार का बड़ा भाग है, वे तब तक अधिक प्रतिद्वंद्वियों का स्वागत नहीं करेंगे, जब तक उन्हें विश्वास न हो जाये कि नवागतों के प्रवेश की पर्याप्त गुंजाइश है और मौजूदा फर्मों का कारोबार प्रभावित नहीं होगा।

इसलिए भीमकाय फर्मों का व्यापक भाग उन उद्योगों में नयी फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत देने में उदार (खुले द्वार की) नीति का समर्थक नहीं, जो मांग में कमी की पहले से शिकार हैं। इसी प्रकार डालर या पाउंड स्टर्लिंग भंडार (स्टाक) तेजी से घट रहा है। इन मुद्राओं की अतिरिक्त आय इतनी अधिक नहीं जो एक उदार आयात नीति के लिए आवश्यक है। इन सबके अलावा सूखे ने खाद्य तेल के बड़ी मात्रा में निर्यात को लाजिमी बना दिया है और पेट्रोल (एक जरूरी निर्यात जिंस) का अंतरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ गया है। इस हालत में निर्यात प्रतिबंध लागू करना पड़ेगा। यह उदारीकरण की नीति के लिए कदापि ठीक नहीं।

बहरहाल सबसे अहम जरूरत है एक नयी छवि की। एक गरीब-समर्थक, धनी विरोधी सरकार की छवि। क्योंकि मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी क्या गारंटी कि अधिसंख्य कांग्रेस संसद सदस्य, यह अनुभव होने पर कि राजीव गांधी आम चुनाव के विकट संघर्ष में उनके रक्षा कवच सिद्ध नहीं होंगे, अपने नेता का साथ नहीं छोड़ेंगे? हर स्थिति में सामान्य आम चुनाव में केवल २७ महीने बाकी हैं। छवि रातों-रात बन-संवर नहीं सकती। इसमें वक्त लगता है।

इसलिए आर्थिक नीति के चंद पहलुओं को बदलना पड़ेगा। समाजवाद के शब्दाडम्बर को और व्यापक करना पड़ेगा और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रेडियो और टेलीविजन के द्वारा इसकी घुट्टी पिलानी पड़ेगी। गत ढाई वर्षों तक जो नीति अपनायी गयी है, उससे पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। इसलिए अधिक संभावना है एक चुने हुए 'उदारीकरण' की। कुछ टुकड़े कभी-कभार गरीबों की तरफ फेंक दिये जायेंगे और कुछ मामूली झटका धनिकों को दिया जायेगा। फिर प्रधानमंत्री को समाजवाद में अपने नये मुल्ला होने का माकूल सबूत देना मुमकिन होगा।

—मालिनी चक्रवर्ती

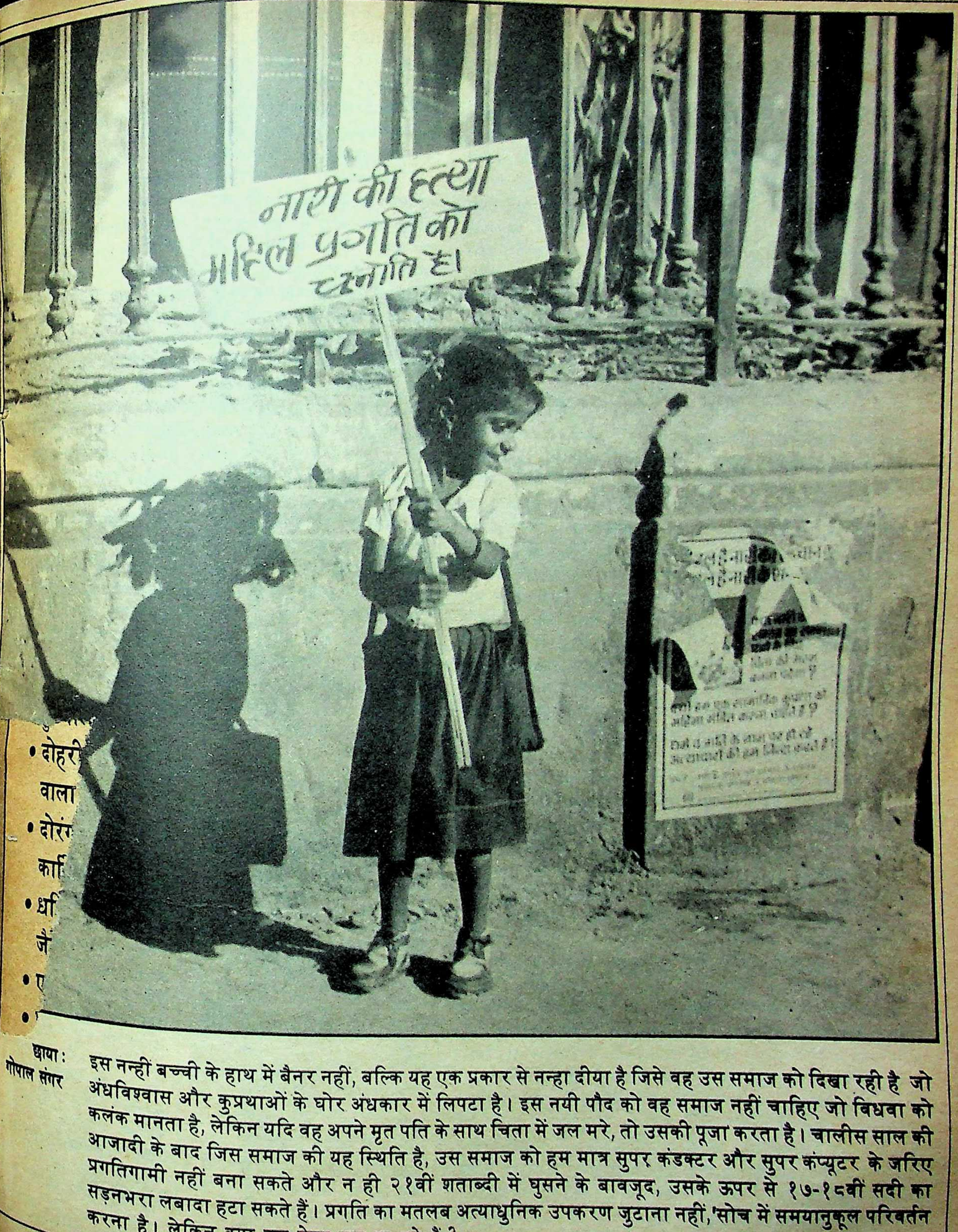

छाया :
गोपाल संगर

इस नन्हीं बच्ची के हाथ में बैनर नहीं, बल्कि यह एक प्रकार से नन्हा दीया है जिसे वह उस समाज को दिखा रही है जो अंधविश्वास और कुप्रथाओं के घोर अंधकार में लिपटा है। इस नयी पौद को वह समाज नहीं चाहिए जो विधवा को कलंक मानता है, लेकिन यदि वह अपने मृत पति के साथ चिता में जल मरे, तो उसकी पूजा करता है। चालीस साल की आजादी के बाद जिस समाज की यह स्थिति है, उस समाज को हम मात्र सुपर कंडक्टर और सुपर कंप्यूटर के जरिए प्रगतिगामी नहीं बना सकते और न ही २१वीं शताब्दी में घुसने के बावजूद, उसके ऊपर से १७-१८वीं सदी का सड़नभरा लबादा हटा सकते हैं। प्रगति का मतलब अत्याधुनिक उपकरण जुटाना नहीं, 'सोच में समयानुकूल परिवर्तन करना है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं?

पुरी के शंकराचार्य निरंजन देवतीर्थ

राजस्थान में पिछले कई वर्षों में सती होने की कई घटनाएं हुई हैं, पर ४ सितंबर, १९८७ को राजस्थान के दिवराला गांव में युवा रूपकंवर के सती होने की घटना ने न केवल राजस्थान सरकार को, ब्लकि देश के अनेक हिस्सों को झकझोर कर रख दिंया है। कोई इसे बर्बरता से की गयी हत्या मानता है, तो कोई धर्म के नाम पर इसके औचित्य को साबित करने में लगा है। सती-विरोध में तीखी प्रतिक्रिया आते ही राजस्थान सरकार ने सती प्रथा को रोकने के लिए एक अक्तूबर को एक अध्यादेश जारी किया, तो एक बार फिर माहौल गरम हो गया। अध्यादेश आते ही राजनेताओं की भूमिका बदल गयी—विरोध और समर्थन का सिलसिला शुरू हो गया। राजनेता ही नहीं इस रणक्षेत्र में धर्म के पुरोधा शंकराचार्य भी उतर आये हैं।

पुरी पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य निरंजन देवतीर्थ ने अध्यादेश आते ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजस्थान के राजपूतों को एकत्र करके सरकार के विरोध में आंदोलन करवाने और सती प्रथा का समर्थन करने के लिए उन्होंने अपने दो शिष्यों प्रबल ब्रह्मचारी और आशुतोष ब्रह्मचारी को राजस्थान भेजा। स्वयं भी शीघ्र ही पहुंचने की घोषणा कर चुके हैं। सती-प्रथा का विरोध करनेवालों के जवाब में पुरी शंकराचार्य कहते हैं कि जो लोग भारतीय संस्कृति के नाम पर अपना पेट पाल रहे हैं, उन्हें सती-प्रथा का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करते समय उनकी जिह्वा क्यों नहीं गल जाती। सती-प्रथा का विरोध करनेवाला गोहत्या के समान पाप का भागी है।

वेद, इतिहास, पुराण, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का हवाला देते हुए शंकराचार्य का कहना है कि धर्म में इस बात की इजाजत है कि जो स्त्री स्वेच्छा से सती होना चाहती है, उसे रोकने का कोई विधान नहीं है। मुगलकाल में हजारों क्षत्राणियां सती हुईं। अपने सतीत्व रक्षा के लिए प्राणों का मोह त्यागना हमारे देश के नारियों का चरित्र है। वे पति के साथ 'कन्ट्रैक्ट' नहीं करतीं। पति से उनका जन्म-जन्मांतर का रिश्ता होता है।

सरकार के सती-प्रथा विरोधी रवैये की खिल्ली उड़ाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जो सरकार अरबों-खरबों रुपए खर्च करके गर्भपात कराती है, भ्रूणहत्या करती है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि अपने पति के साथ सती होनेवाली स्त्री पर रोक लगाये। जब सरकार इस बात की इजाजत देती है कि कोई लड़की अपने माता-पिता, बंधु-बांधव की परवाह किये बिना, स्वेच्छा से अपनी इच्छा के व्यक्ति से विवाह कर सकती है, तो वह पति के साथ सती होने की स्वतंत्रता से कैसे वंचित की जा सकती है।

शंकराचार्य के अनुसार जो नारी मन, वाणी और कर्म से स्वप्न में भी अपने पति के सिवा संसार में किसी को पुरुष ही न समझे, वह उत्तम कोटि की सती है। जो धर्मशास्त्र की मर्यादाओं का अनुसरण करके पति को ही अपना सर्वस्व समझे, वह मध्यम कोटि की सती है। लोकलज्जा और भय से जो पत्नी अपने पति के सिवा परपुरुष से संबंध न रखे, वह अधम कोटि की सती है। जो स्त्री सती न होना चाहे उसके साथ किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती के समर्थक शंकराचार्य नहीं हैं। उनका मानना है कि स्वेच्छा से सती होनेवाली स्त्री को रोकना पाप है। जोर-जबरदस्ती से सती करना महापाप है। राम के पिता दशरथ की मृत्यु पर तीनों रानियां सती नहीं हुई थीं। मतलब यह है कि धर्म स्वेच्छा से सती होने की स्वतंत्रता देता है।

शंकराचार्य का मानना है कि पतिव्रता नारी के दर्शन करने से भगवान शंकर और पार्वती के साक्षात दर्शन होते हैं। इसी आधार पर शंकराचार्य सती-प्रथा के समर्थन में अपने शरीर के अंतिम रक्त की बूंद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्हें मृत्युदंड तक स्वीकार है।

सती-प्रथा का विरोध करनेवाले राजनेताओं को आड़े हाथों लेते हुए शंकराचार्य का कहना है जो नेता चुनाव जीतने के लिए अपने विपक्षी की हत्या करवाते हैं, अपनी मां, बहन, बेटी को गिरवी रख देते हैं, धर्म और संस्कार का गला घोंटते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी पत्नियों का व्यापार करते हैं, क्या उनके विचार दकियानूसी नहीं हैं। मैं उस लोकतंत्र का कतई समर्थन नहीं कर सकता, जिसके नादिरशाही जूतों तले संस्कारों को रौंदा जाये और धर्म को हेय दृष्टि से देखा जाये।

शंकराचार्य के अनुसार जोर-जबरदस्ती से किसी को सती कराना महापाप है, तो शंकराचार्य को सती प्रथा का समर्थन करते समय यह जरूर सोचना चाहिए कि रूपकंवर स्वेच्छा से सती हुई या उसे जोर-जबरदस्ती से सती कराया गया। अगर रूपकंवर जोर-जबरदस्ती से सती करायी गयी है, तो शंकराचार्य क्या कार्रवाई करेंगे, इसे भी उन्हें देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए।

जेनिया

एथलीट शब्द जुबान पर आते ही एक तस्वीर उभरती है—उड़नपरी पी०टी० उषा की। पर कल पी०टी० उषा की जगह आपकी जुबान पर जेनिया का नाम हो सकता है, जब पी०टी० उषा की तरह कीर्तिमानों का ढेर लगाने के लि बंबई की १५ वर्षीया, पांच फुट इंच लंबी इकहरे बदन की जेनि अंतरराष्ट्रीय परमिट एथलेटि चैंपियनशिप की १०० मीटर दौ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर होगी।

जेनिया को भारत की दूस उड़नपरी बनाने का बीड़ा उठाया पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स के 'लिमका' ने सितंबर महीना जेनिया के लिए बहु ही अच्छा रहा। सितंबर के प्रथ सप्ताह में जेनिया को अंतरराष्ट्री परमिट मीट में हिस्सा लेने के लि भारतीय टीम में चुना गया, तो उसके एक सप्ताह बाद ही 'लिमका' ने उसे एथलेटिक की दुनिया में आगे ले जाने के लिए गोद ले लिया। गोद लेते समय 'लिमका' की ओर से घोषण की गयी कि 'लिमका' उसे १५०० रुपए माहवार देगी। इसके अलावा संपूर्ण एथलेटिक किट और अन्य सुविधाएं भी।

जेनिया ने सात वर्ष की उम्र से दौड़ना शुरू किया और दौड़ती जा रही है। बंबई की जीसस मेरी फोर्ट की दसवीं कक्षा की छात्रा जेनिया ने पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी है। दो वर्ष पहले उसने ग्रेटर बंबई मीट में पी०टी० उषा का सौ मीटर दौड़ का १२.५ सेकेंड का जूनियर रिकार्ड, यह

फासला १२ की संभावना से
तोड़ा था। जे की क्या गारंटी
और बंग ह अनुभव होने
राष्ट्रीय ंकट संघर्ष में
१०० और २० पने नेता का
रिकार्ड समय ामान्य आम
अगरतला में छवि रातों-
राष्ट्रीय एथलेटि लगता है।
जेनिया ने रजत- हलुओं को
इसी वर्ष ५ सि को और
स्टेडियम में परमि र्ण ढंग से
चयन ट्रायल में उस की घुट्टी
दौड़ में सीनियर नीति
राय और कुमकुम झाड़ा
छोड़ते हुए १२.४ सेके क चुने
भार

निरंतर ट्रैक पर आग

जेनिया की निगाहें अगले वर्ष सियोल ओलंपिक और १९९ बीजिंग एशियाड पर टिकी जेनिया को आजकल प्रख्यात आ जहांगीर सुमारीवाला की देखरे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

—दिनेश

संस्थापक: स्वर्गीय श्री क्षितीन्द्रमोहन मित्र। सम्पादक: आलोक मित्र। श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि
इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

17/11/87
[illegible] विभाग

मनोरमा

१५ दिसम्बर '८७

बुनाई विशेषांक

बुनाई की दिलकश डिजाइनें

प्रमुख आकर्षण

- एक पुलोवर पार्टी में पहनने के लिए
- नये फैशन का बैगी टॉप
- एक पुलोवर यूनीसेक्स
- क्या कहने कढ़े कार्डिगन के !
- फर से सुसज्जित हुडवाला पुलोवर
- दोहरी उपयोगिता वाला ट्विन सेट
- दोरंगा मनमोहक कार्डिगन
- धनिये की बुनाई वाली जैकेट
- एक स्वेटर दोरंगा
- एक पुलोवर नये नमूने का
- कढ़ा हुआ ट्विन सेट
- सादगीपसंद युवाओं के लिए एक खूबसूरत पुलोवर

आवरण कथा :

इतवार को झगड़ा सोमवार को प्यार, पति-पत्नी का यह कैसा व्यवहार

पति-पत्नी में आज झगड़ा तो कल प्यार—यह एक बहुत सामान्य सी चीज है, पर यही झगड़ा अगर जल्दी ही सुलह में न बदले तो मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं ! पति-पत्नी को इन झगड़ों के संबंध में कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए ?—पति-पत्नी के संबंधों पर एक रोचक, विचारपूर्ण रचना :

मूल्य रु० ६/-
दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक प्रकाश्य

अन्य आकर्षण

मेरी सुहागरात :

'उस रात पतिदेव घर ही नहीं आये'

व्यंजन :

सरदी के सदाबहार स्वाद

सौन्दर्य :

आपके सौन्दर्य को निखारे : फेस मास्क

विशिष्ट रचना :

आ जा री निंदिया....

दिलचस्प लेख :

सफाई सनक की हद तक तो नहीं

बच्चे और आप :

'मम्मी अब तुम मुझे प्यार नहीं करतीं'

दस्तकारी :

घर पर ही बनाइये 'ग्रीटिंग कार्ड्स'

दीपक शर्मा की कहानी

—लीक

सुप्रसिद्ध उर्दू व्यंग्यकार सआदत हसन मंटो की व्यंग्य रचना

—नाश्ता

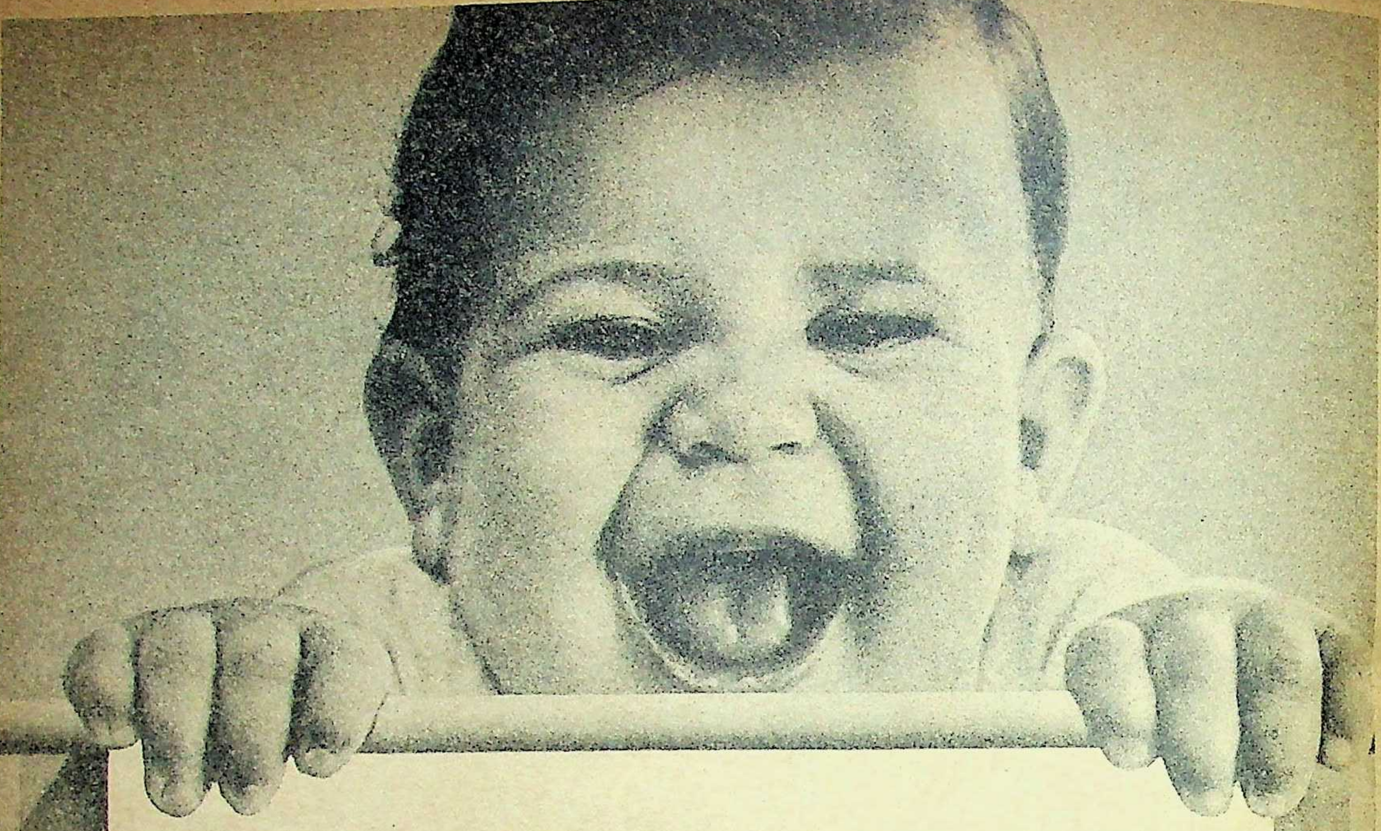

स्वाद भी पाए. बढ़ता भी जाए... मुन्ना फ़ैरेक्स® के साथ-साथ.

अपने शिशु का वज़न व क़द जाँचिये *	बेटा		बेटी	
	वज़न	क़द	वज़न	क़द
उम्र ३ महीने तक	५.२ कि.ग्रा.	५९.१ सें.मी.	४.९ कि.ग्रा.	५८.४ सें.मी.
उम्र ६ महीने तक	६.७ कि. ग्रा.	६४.७ सें.मी.	६.१ कि.ग्रा.	६३.७ सें.मी.
उम्र ९ महीने तक	७.३ कि.ग्रा.	६८.२ सें.मी.	६.९ कि.ग्रा.	६७.० सें.मी.
उम्र १२ महीने तक	८.४ कि.ग्रा.	७३.९ सें.मी.	७.८ कि.ग्रा.	७२.५ सें.मी.

* इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किया गया.

भारतीय शिशुओं के लिए यह केवल एक औसत है. अगर आपका डॉक्टर शिशु के विकास से संतुष्ट है तो चिंता की कोई बात नहीं.

रंगीन 'बेबी केअर गाइड' पुस्तिका मुफ़्त मंगाने के लिए लिखिये :
ग्लैंडिया लि. (FPD/ 245),
डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली,
बम्बई-४०० ०२५.

Delicious
Farex®
CEREAL WITH MILK

शिशु के चहुमुखी विकास और वृद्धि के लिए उसे पौष्टिकता से भरपूर आहार "फ़ैरेक्स" दीजिये.

फ़ैरेक्स®
शिशु बढ़े. फूले-फले...
जब फ़ैरेक्स मिले

CLARION/B/26/244 HIN

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक २१

नवंबर प्रथम पक्ष, १९८७

माया

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र

प्रधान संपादक
आलोक मित्र

संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा

उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू

ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार

वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रजना कक्कड़

विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा

संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी

कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी

सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

यह अंक

माया
हिन्दू उग्रवाद का शंखनाद

आवरण कथा

अब तक अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित समझते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण देश की आबादी में ८० प्रतिशत स्थान रखने वाले हिंदुओं में ऐसी धारणा पैदा हो रही है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इस धारणा के सहारे कुछ हिंदू संगठन बहुसंख्यकों को गोलबंद करने में जुट गये हैं। यह गोलबंदी क्या रूप ले रही है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ३०

'हबूड़ा' व 'भातू'

१९२२ में अंग्रेजों ने जरायमपेशा घोषित कर जिन 'हबूड़ा' व 'भातू' जनजातियों को कानपुर के समीप बसाया था, आज वे किस हाल में हैं? ८४

डिंपल

एक दशक तक गुमनाम रहने वाली डिंपल ने अपनी ताजा फिल्मों में ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया कि उन्हें श्रीदेवी और स्मिता का विकल्प कहा जाने लगा है? ७४

राजस्थान

क्या प्रशासनिक अधिकारी नीमरोट में रिश्वत लेने और उनकी हत्या करवाने के पीछे मुख्यमंत्री जोशी के पुत्र का हाथ है? ५७

गायकवाड़

अपनी वैभव सम्पदा के लिए विख्यात बड़ौदा रियासत के राजकुमार फतहसिंह का अतीत और वर्तमान: १३

मध्य प्रदेश

बिलासपुर के पांडातराई स्थित महामाया मंदिर में हरिजन-प्रवेश के नाम पर जातीय संघर्ष किसने भड़काया? ६३

पश्चिम बंगाल

मार्क्सवादियों पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि उन्होंने जमीनों को लीज पर देने के १४ सौदों में ३०० करोड़ रुपए की दलाली खायी है? ६९

दिल्ली दरबार: व्यापक भूमिका का रीगनी टेप ६
खबरों के आगे, खबरों के पीछे ८
फोटोफीचर ९
वामपंथियों का खेल २१
तथ्य-कथ्य: रिलायंस कप में बने रिकार्ड २८
आवरण कथा: पुरी के शंकराचार्य का साक्षात्कार ३४
खेल: एक अविस्मरणीय पारी ४६
चौधरी चरण सिंह की बेटी ने आत्महत्या क्यों की? ४९
कार्टून ५२
औरंगाबाद हत्याकांड की छमाही ५३
बेढब ६१
महाराष्ट्र: दादा का नया पैंतरा ६६
फिल्म: डिंपल: मैं दुबारा शादी करूंगी ७८
परदे के पीछे ९४
रैली का अर्थशास्त्र ९७
रैली की राजनीति १००
पड़ोस: श्रीलंका के भूमि विकास मंत्री दिस्सानायक का साक्षात्कार १०२

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

आवरण पारदर्शी: सुनील सक्सेना (त्रिशूलधारी साधु), विजय सिंह (शंकराचार्य)

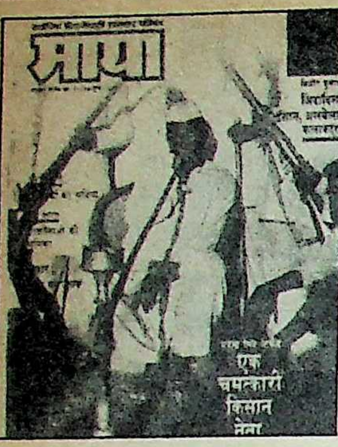

धर्म की ओट में स्त्रीदहन

'माया' के अक्तूबर प्रथम पक्ष में 'धर्म की ओट में स्त्री दहन' पढ़ी। सचमुच, धर्म की ओट में ऐसे-ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं, जिन्हें मद्दे नजर रखते हुए ऐसे धर्म को धर्म कहना धर्मान्धिता है, अमानववा है। गांधीजी के शब्दों में, "धर्म वह है जो मानव को मानव बनाये रखता है, अन्यथा वह अधर्म है, त्याज्य है।" इन्हीं धर्मों ने अनेक रूपकंवरों की नृशंस हत्याएं की हैं। इस विज्ञान के युग में भी, गंवार तो गंवार, शिक्षित लोगों का भी कुधर्मों की मृगतृष्णा में भागे जाना, जितना हास्यास्पद है उतना ही दुखद भी।

वस्तुत: एक रूपकंवर को सती-प्रथा की धर्मान्धिता में जिंदा जला दिये जाने पर इस कुप्रथा के विरोध में जितना शोर मचाया जा रहा है, पाण्डित्यपूर्ण लेख लिखे जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वे व्यवहारिकता की कसौटी पर खोखले हैं, भ्रामक हैं, अर्थहीन हैं, दिशाहीन हैं। जो इन बातों को सती-प्रथा के विरुद्ध एक क्रांति मान रहे हैं, वे तो मृगमरीचिका में हैं। सत्यता जानने के लिए हमें अपने समाज पर दृष्टिपात करना होगा। रूपकंवर को तो उसके पति की मृत्यु के पश्चात आग में झोंका गया,पर नववधुओं को तो भरपूर दहेज न लाने के कारण पति के जीवित रहते झोंक दिया जा रहा है। जिंदा रखकर जिंदगी भर ताने दिये जाते हैं, सताया जाता है। —विजय कुमार गुप्ता, मंत्री, श्री सेवा सदन पुस्तकालय, कासिम बाजार, मुंगेर, बिहार

सती, अपनी इच्छा से हुई

मैंने 'माया' अक्तूबर प्रथम अंक में 'धर्म की ओट में स्त्री दहन' पढ़ा। मुझे इस लेख के शीर्षक पर एतराज है। हमारे समाज में कभी भी इस प्रकार की 'सती-प्रथा' नहीं रही और न ही हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना हो। पर रूपकंवर सती अपनी इच्छा से हुई है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज डेढ़ महीना हो गया, कोई-न-कोई तो गवाही देता कि उसके साथ जबरदस्ती की गयी। रूपकंवर में 'सत' था तभी तो वह सती हुई। श्रीमानजी सती तो करोड़ों में एक होती है। यह सब राजपूतों को बदनाम करने की साजिश है। वरना यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे इतना उछाला जाये। इस प्रकरण में इन नेताओं की चाल सफल नहीं होगी। इसका उल्टा ही प्रभाव होगा। —गिरधारी सिंह चंपावत, मु०/पोस्ट-सरेचां, जोधपुर, राज०

भगवान. हमें अक्ल दो

'धर्म की ओट में स्त्री-दहन' (माया, अक्तूबर प्रथम पक्ष) पढा। कहा जाता है कि जब बच्चे को मां मारती है, तो बाप बचाता है और बाप मारता है, तो मां। यदि दोनों ही मारें तो राजा का दायित्व है उसकी रक्षा करने का, लेकिन रूपकंवर को तो उसके सभी अपनों ने मिलकर मार डाला। राजा (शासन) भी मौन सहायक बनकर देखता रहा।

कार्ल मार्क्स का यह कथन सच ही लगता है कि 'धर्म अफीम की तरह है', तभी तो चीटियों तक को आटा खिलाने वाले हिंदू एक अट्ठारह साल की युवती को जीवित जला सके। ईश्वर रूपकंवर की आत्मा को शांति तथा हम हिंदुओं को 'अक्ल' दे। —सुरेंद्र सिंह दांगी, ग्रा०पो०—कुल्हार, गंजवासौदा, म०प्र०

राजपूत नजरिया बदलें

देवराला के रूपकंवर सती कांड पर अक्तूबर के अंक में व्यापक सामग्री देकर आपने पुलिस, समाज, परिवार व प्रशासन की निष्क्रियता के सारे तथ्यों को उजागर कर दिया है। सती कांड या सती-प्रथा को ऐतिहासिक आधार पर समर्थन देकर सही व महान कृत्य करार देने वाले राजपूत इतिहास का एकतरफा अध्ययन कर पाये हैं। वे शायद इस तथ्य को भूल जाते हैं कि सती-प्रथा जिस काल में उचित मानी जाती थी वैसी परिस्थितियां आज नहीं हैं।

—ज्ञानेश चौबे, हरदा, म०प्र०

कितना स्वतंत्र है लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ लोकतंत्र में ?

अक्तूबर प्रथम पक्ष की 'माया' में प्रकाशित आवरण कथा 'राजीव बनाम गोयनका' रपट पढ़ी। सचमुच आज सरकार के मुखिया और एक भीमकाय समाचार प्रतिष्ठान के मालिक के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ गया है। दोनों का दावा है कि वह लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुपालक और रक्षक हैं। यह तो समय ही बतायेगा की इस उठा-पटक में कौन गच्चा खायेगा, क्योंकि इस लड़ाई का फैसला अब जनता की अदालत करेगी। मैं यह मानता हूं कि देश के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार का भारतीय संविधान में प्राविधान है, फिर भी निहित स्वार्थों के खातिर 'प्रेस की आजादी' पर कुठाराघात करके देश के नागरिकों से यह अधिकार छीना जा रहा है। नि:संदेह प्रेस की आजादी पर हमला देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को चुनौती देना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लेकिन उस समय हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, जब हमारे सामने ही लोकतंत्र का चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस को सरेआम चौराहे पर खींचकर प्रताड़ित किया जाता है। 'इंडियन एक्सप्रेस' पर 'राजस्व खुफिया निदेशालय' (डी०आर०आई०) द्वारा डाला गया छापा इसका एक जीता-जागता उदाहरण है, क्योंकि 'एक्सप्रेस' पर पड़े छापे ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यद्यपि 'इंडियन एक्सप्रेस' भारतीय प्रेस की आजादी का प्रतीक बन गया है, किंतु इस कटुसत्य से किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता कि एक्सप्रेस समूह पर घृणित हमले के पीछे उन लोगों की जुबान काट देने का षड्यंत्र था जो उच्चवर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने और अखबारों के नैतिक कर्तव्यों व दायित्वों में विश्वास रखते हैं।

साक्ष्य व परिस्थितियां चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि 'इंडियन एक्सप्रेस' पर पड़ा छापा मात्र बदले की भावना का परिणाम था। उक्त समूह छपाई मशीनों को विदेश से आयात करने वाला अकेला समूह नहीं था, फिर सिर्फ इसी 'प्रेस समूह' के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही क्यों की गयी? आश्चर्य की बात तो यह है कि 'इंडियन एक्सप्रेस' जैसे समूह में छापा पड़े और देश के विशिष्ट व जिम्मेवार व्यक्ति को इसकी भनक तक न लगे। क्या इस प्रकार के राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्व छापे की जरूरत थी? जबकि सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की तुलना में लगाये गये आरोप बौने सिद्ध हो चुके हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' पर छापे की घटना तो मात्र एक इत्तफाक है, पर 'प्रेस की हत्या' और 'पत्रकार-उत्पीड़न' की घटना आम बात हो गयी है। नादिरशाही के परिणामस्वरूप आज हम यह सोचने के लिये मजबूर हो गये हैं कि 'विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कितना स्वतंत्र है?' और क्या देश के नागरिकों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार छीना जा रहा है? — विश्वतारा दूसरे, सिंचाई कार्यालय (नदिया के पार), चित्रकूटधाम, कर्वी, बांदा

सत्यजीत रे

० मैं स्वीकार करती हूं कि मैं असफल हो गयी हूं। मैं ही क्या हमारी पूरी पीढ़ी असफल हो गयी है।
—श्रीमती मारग्रेट

० जनमत के ऊपर नहीं है कानून... रूपकंवर के सती होने पर सरकार जनता का ध्यान समस्याओं से हटाने के लिए बावेला खड़ा कर रही है। **—काशी सुमेरु मठ के शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती**

० यद्यपि गोरखालैंड मसले पर हमारे विचार ज्योति बसु से नहीं मिलते फिर भी मैं उनकी इज्जत करता हूं। वह देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। **—जी०एन०एल०एफ० के अध्यक्ष सुवास घीसिंग**

० हालत यह हो गयी है कि विपक्ष मदारी हो गया है और श्री (वी०पी०) सिंह को अपनी धुन पर नचा रहा है। **—गुलाम नबी आजाद 'टेलीग्राफ' में।**

० जनमोर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूर रहेगा।
—विश्वनाथ प्रताप सिंह, दैनिक जागरण में।

० आप मौत से कुछ इंच बचे हैं और मैं कुछ सेकेंड।
—श्रीलंका के राष्ट्रपति जूनियस जयवर्धने, दक्षेस सम्मेलन के दौरान

० हम चाहें या न चाहें इक्कीसवीं शताब्दी में तो अपने आप चले जायेंगे, लेकिन हम अपने साथ सती-दाह और ६० प्रतिशत निरक्षर लोग ले जायेंगे। **—ज्योति बसु**

० सती कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मीडिया ने इसे बढ़ा दिया है। पता नहीं ऐसे कितनी ही स्त्रियां जला दी जाती हैं। **—बसंत दादा पाटील**

० कांग्रेस-इ और राजीव गांधी दोनों ही सांप्रदायिक नहीं हैं। **—नंबूदिरीपाद**

० जिन दलों के ३-४ प्रतिनिधियों से ज्यादा लोकसभा में नहीं हैं, उन दलों को उस दल के निर्णयों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं, जिसके ४१५ सदस्य लोकसभा में हैं। **—श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी**

० मैं उस टाइप की नहीं हूं कि रोल हथियाने के लिए कम कपड़ों में आ जाने के लिए राजी हो जाऊं या और कोई तिकड़म भिड़ाऊं। **—पूनम ढिल्लो, माधुरी में**

० मैं उन भारतीयों के लिए बिलकुल अजनबी हूं जो बंगाली नहीं जानते। इसलिए मैं अपने देश से बाहर जाना चाहता हूं। **—सत्यजित रे**

वी०पी० सिंह

पूनम ढिल्लो

सती प्रथा पर विशेष

आवरण कथा

राजस्थान का रूपकंवर कांड-सती प्रथा को जिन्दा रखने की साजिश

आज के भारत में भी सती प्रथा के प्रचलन और समर्थन के पीछे निहित कारणों, कानूनी मुद्दों और उनके अमल में रुकावटों की जांच-पड़ताल के साथ विस्तृत विवेचनापूर्ण कथा

अन्य प्रमुख आकर्षण

• मासूम कविता की बलि

दिल्ली में डेढ़ बरस की बच्ची को अंधविश्वासियों द्वारा बलि चढ़ा देने की पृष्टभूमि क्या थी?

• बिहार के तांत्रिक अधिकारी का स्कैण्डल

दुमका के जिला जन संपर्क अधिकारी सुरेश पाण्डेय अपने तांत्रिक चमत्कारों की आड़ में गरीब लड़कियों के यौन-शोषण के अभियुक्त कैसे बने?

• जैकी श्राफ की दीवानी गीता

फिल्म अभिनेता जैकी श्राफ की 'हीरो' फिल्म देख-देखकर नेपाल की एक युवती अपने बच्चों और पति को छोड़कर जैकी के पास बंबई जा पहुंची और तमाशा बन गयी

• प्रेम-त्रिकोण का चौथा कोण

फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के दूसरे प्रेम-विवाह की अत्यन्त रोचक कहानी

नवम्बर, '८७

मनोहर कहानियाँ

मूल्य रू० ६/- आज ही अपने अखबार विक्रेता से खरीदें।

'व्यापक भूमिका' का रीगनी टेप

दिल्ली दरबार जब बारह दिनों की विदेश यात्रा के बाद लौटे तो कतारों में 'टीनोपाली सफेदी' हुजूम उनके इर्दगिर्द एकत्र होने लगा। उन्होंने घबराकर इधर-उधर देखा, तो सामने से फाइलों में डूबे गोपी (चंद जासूस) अरोड़ा दिल्ली दरबार से टकरा गये। टकराते ही गोपीजी की गोपियां (फाइलें) जमीन पर बिखर गयीं। वह गोपियों को संभालें कि उसके पहले दिल्ली दरबार ने गोपी अरोड़ा को जकड़ लिया—"ये इंकाई सांसद, टीनोपाली सफेदी में कफनिये, मेरे इर्दगिर्द क्यों जमा हो रहे हैं?" गोपी अरोड़ा ने अपना चश्मा संभाला—"सर, ये लोग आपको राष्ट्रपति भवन ले जाने के लिए आये हैं। इनका कहना है कि आपने इन लोगों को कहा है कि संसद के ठंडे अधिवेशन के शुरू होने के पहले इन सभी को मंत्रिपद की कसम दिला दी जायेगी।" दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गये—"यह क्या मजाक है! मेरे पास इन छोटे-मोटे कामों के लिए समय कहां है। अरे, तुमने सुना नहीं अमरीका के रीगन भाई ने मुझको क्या कहा कि मैं अपने मुल्क में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। बड़े भाई का कहना तो मानना ही पड़ेगा। इन लोगों को कह दिया जाये कि मेरे पास मंत्रिमंडल विस्तार आदि के लिए समय नहीं है।" यह कह कर दिल्ली दरबार 'महत्वपूर्ण भूमिका' अदा करने के लिए अपने मेक-अप रूम में घुस गये।

आगे की कतार में टीनोपाली सफेदी में कफनियाये भगवत झा आजाद,, दिनेश सिंह, दरबारा सिंह आदि की तरफ गोपी अरोड़ा ने जब मुखातिब होकर दिल्ली दरबार के फरमान को दोहराने की कोशिश की, तो उन लोगों ने उनको धकिया दिया—"पीछे के लोगों से कहो, हम लोगों ने सुन लिया है।" रघुनन्दन लाल भाटिया गोपी अरोड़ा की तरफ लपके, तो उनको भगवत झा आजाद ने अपनी ओर खींच लिया—"आओ, बाहर चलो, मैं बताये देता हूं कि दिल्ली दरबार का क्या फरमान है।" भाटिया के साथ कई और लोग भगवत झा आजाद के साथ हो लिये, लेकिन तिफंगे पैजामे में लुढ़कते हुए कल्पनाथ राय ने गोपी अरोड़ा का गिरहबंद पकड़ लिया—"मंत्री बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस अधिकार के लिये मर-कट जायेंगे।" कल्पनाथ राय गोपी अरोड़ा से हाथापाई पर उतरें कि उसके पहले भगत (एच०के०एल०) बिना कालर की सफारी में आ गये—"कल्पनाथजी, हम पालीटिशनों को ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं भिड़ना चाहिए। इन बेचारों की बहुत मजबूरी होती है। बिल्ली के भाग्य से छींका टूट चुका है और आप मंत्री बन चुके हैं। आप तो इन ब्यूरोक्रेट्स की मजबूरियां भलीभांति जानते ही हैं। गोपीजी से आप हाथापाई पर क्यों उतारू हो रहे हैं।" कल्पनाथ राय ने गोपी को छोड़ कर भगतजी की बिना कालर की गरदन दबोच ली—"मंत्री न होने के दर्द को तो लगता है तू भूल ही गया। अबे भंगत के बच्चे मंत्री की कुरसी पर तूने तो अपनी आंख पूरी तरह लगा रखी है, इसीलिए वह तेरी आंख से ओझल नहीं हो पाती है। लेकिन हम लोग क्या करें जो आंखों से मंत्री की कुरसी को देखते हैं और वह ओझल हो जाती है।" बीच में भारत माता उर्फ शीला दीक्षित फट पड़ीं—"कल्पनाथजी, यह क्या हो रहा है। कुछ तो संसदीय मर्यादाओं का पालन करें। आप सांसद हैं और यह भगतजी संसदीय कार्यमंत्री।" कल्पनाथ राय ने भगतजी की गरदन को छोड़ दिया—"शीलाजी आप बीच में न आया करें। आपको देखते ही मैं अपनी पहलवानी भूल जाता हूं।" शीला दीक्षित भगतजी को कल्पनाथ राय के पंजे से छुड़ा कर ले जाने लगीं, तो भगतजी ने जाते-जाते धमकी के स्वर में कहा, "कल्पनाथ राय मैं तुझे देख लूंगा। तू अपने को बहुत तीसमारखां समझता है...।" कल्पनाथ राय भगत की तरफ फिर लपके—"अबे तू मुझे क्या देखेगा, तेरा तो काम वह चुरहट लाटरी वाला ठाकुर अर्जुन सिंह कर देगा।"

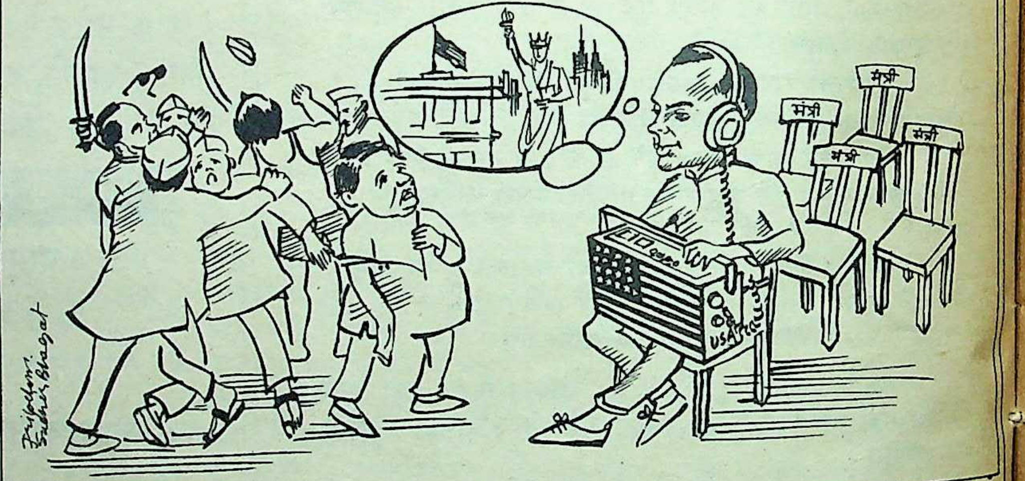

दिल्ली दरबार से तमाम इंकाई सांसद बाहर निकल आये। भगवत झा आजाद पहले से ही पंचम में चीख रहे थे—"इंका की महामंत्रीगिरी छीनी गयी थी, तो साफ-साफ इशारा किया गया था कि 'महा' दिल्ली दरबार में रख ली जायेगी, लेकिन 'मंत्री' बतौर खैरात वापस कर दी जायेगी। अब इस 'झा ब्राह्मण' को भिक्षा देने से इनकार किया जा रहा है। यह भारत की गौरवमयी परम्परा और संस्कृति पर सीधा कुठाराघात है। इसको इस देश का जन-मानस कभी बरदाश्त नही कर सकता है। हम लोगों को देश की प्राचीनतम विरासत को बचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम लोगों को भी जनमोर्चा बनाना पड़ेगा...।" इंकाई सांसदों में भारी उत्तेजना फैलने लगी। पीछे से कल्पनाथ राय ने भीड़ में घुसने के पहले अपना टीनोपाली सफेद कुरता 'चर..चर' करके फाड़ डाला—"यह देखो इस भूमिहार का क्या हाल किया गया है। मुझसे कहा जा रहा था कि पितृ पक्ष में मंत्री-पद की शपथ ले लो। मैंने इनकार कर दिया कि इस समय मंत्री क्या प्रधानमंत्री पद की भी शपथ दिलायी जाये, तो मैं नहीं ले सकता हूं। अब मैं जब मंत्री-पद की शपथ लेने के लिए गया, तो मेरा यह हाल किया गया।

दिल्ली दरबार 'मेक-अप' रूम से निकल कर दरबार में 'व्यापक भूमिका' पर रीगनी टेप को फिर से सुनने के लिए आ गये। उसी समय इस्पाती माखन लाल फोतेदार ने दरबार में प्रवेश किया। पहले वह कश्मीरी में बोलने लगे, तो गुलाम नबी आजाद ने गरदन हिलाना शुरू कर दिया। दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गये—"अपनी कश्मीरी बोली? क्या मतलब! कश्मीरी बोली मेरे नाना-परनाना की होगी। रीगन भाई ने मुझे मुल्क के बाहर व्यापक भूमिका का न्योता दिया है। इसलिए अब मुझे अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी में ही मक्खन लगाओ।"

दिल्ली दरबार

दिल्ली दरबार के विशुद्ध अंग्रेजी में मक्खन लगाने के बाद जब फोतेदार मुख्य मुद्दे पर आये, तो उनको बीच में ही रुक जाना पड़ा। दिल्ली दरबार ने फोतेदार को यह कह कर रोक दिया—"अब तुम मेरे पालीटिकल एडवाइजर नहीं हो, तो मुझे पालीटिकल एडवाइस क्यों दे रहे हो?" फोतेदार ने सफाई देते हुए कहा, "सर, मेरे जाने के बाद आपका अभी तक कोई नया पालीटिकल एडवाइजर नहीं बन पाया है, इसलिए मेरा खानदानी फर्ज बनता है कि मैं आपको पालीटिकल एडवाइस दूं।" दिल्ली दरबार ने दरबारियों के चेहरे देखे, तो उनमें कोई विरोध नहीं था। फोतेदार ने संक्षेप में दिल्ली दरबार के सामने अपनी बात को रख दिया—"मंत्रिमंडल का विस्तार न होने से तमाम इंकाई सांसद बहुत नाराज हैं। वे लोग अपना जनमोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं।" दिल्ली दरबार ने अनमने मन से इतना कहा, "मेरे पास मंत्रिमंडल-विस्तार आदि के लिए समय नहीं है। 'मुझे रीगन भाई ने मुल्क के बाहर व्यापक भूमिका निभाने के लिए कहा है। *श्रीलंका* में मेरी भूमिका से वह बेहद खुश हैं। मैं सोच रहा हूं कि फिजी में भी कूद पड़ूं...।" उन्होंने व्यापक भूमिका का रीगनी टेप बजाने का इशारा किया । रीगनी टेप बजने को ही था कि स्ट्रेचर पर लदे सीता राम केसरी आ गिरे। दिल्ली दरबार ने अचम्भित होकर कहा—"यह क्या केसरी, अस्पताल का खूंटा तुड़ाकर क्यों भाग आये! क्या अलविदा कहने आये हो।" केसरीजी ने दोनों हाथ वैश्य वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जोड़ लिये—"सरकार, अभी कोई इरादा नहीं है। फोतेदारजी का फोन गया था कि दिल्ली दरबार में मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से संकट घुस आया है। तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए फौरन से पेश्तर पहुंच जाओ। सो मैं हाजिर हो गया हूं।" दिल्ली दरबार प्रसन्न हो उठे और उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, "सुनाओ थोड़ी देर तुम्हारी भी बकवास सुन ली जाये।"

केसरीजी को यूथ कांग्रेस के कामथ ने सहारा दिया, तो वह उठकर खड़े हो गये। आनन्द शर्मा ने अपनी दाढ़ी में फंसे तिनके को गुस्से में निकाल कर बाहर फेंक दिया। केसरीजी ने बोलना शुरू किया—"हुजूर मंत्रिमंडल का विस्तार अभी कतई न करियेगा। राजा मांडा यानी विश्वनाथ प्रताप सिह इसी घात में बैठा है कि जिनको मंत्रिमंडल में न लिया जाये, उनको वह अपने जनमोर्चा में लेकर दिल्ली दरबार के खिलाफ जहर उगलवायें। हमारे पास दल-बदल कानून का अस्त्र है। कोई हमको छोड़ कर नहीं जा सकता है। और फिर सरकार, आपसे रीगन भाई ने व्यापक भूमिका अदा करने का भी तो आग्रह किया है। आखिर बड़े भाई की बात को ऐसे ही थोड़े टाला जा सकता है। इसके अलावा हुजूर मेरे मंत्री होने का भी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हूं। लोकसभा से तो मुझे कोई मोह नहीं है, राज्यसभा में ही आऊंगा...।" दिल्ली दरबार को केसरीजी का प्रवचन अच्छा लगा। लेकिन गोपी अरोड़ा के पास खड़े केदार नाथ सिह उत्तेजित होने लगे—"सर, मुझे लग रहा है कि हमारे इंकाई सांसदों को मंत्री बनने के लिए सी०आई०ए० बरगला रहा है। हम लोगों को ऐसे सांसदों को सी०आई०ए० एजेंट कह देना चाहिए तो काम चल जायेगा।"

"मेरे पास मंत्रिमंडल-विस्तार आदि के लिए समय नहीं है। मुझे रीगन भाई ने मुल्क के बाहर व्यापक भूमिका निभाने के लिए कहा है। श्रीलंका में मेरी भूमिका से वह बेहद खुश हैं। मैं सोच रहा हूं कि फिजी में भी कूद पड़ूं।"

'सी०आई०ए०' का नाम सुनते ही दिल्ली दरबार आपे से बाहर हो गये। उनका चेहरा तमतमा उठा—"केदार नाथ अगर तुम अमेठी के न होते, तो मैं तुमको दरबार से धक्के मारकर बाहर करवा देता। मैं कह चुका हूं कि अमरीका में बुश भाई (अमरीकी उपराष्ट्रपति) मुझसे साफ-साफ कह चुके हैं कि इंडिया से सी०आई०ए० को हटा लिया गया है। अब हम लोगों को सी०आई०ए० का काम देखना है।" दिल्ली दरबार के आपे से बाहर गुस्से को देखकर केदारनाथ सिह पीछे भीड़ में लुक गये। गोपी अरोड़ा भी दो-चार कदम पीछे होकर दरबार से फूट लिये। दिल्ली दरबार ने फिर से व्यापक भूमिका के रीगनी टेप को बजाने का इशारा किया, तो दरबार में पीछे शोर होने लगा। बघेल ठाकुर अर्जुन सिह राजपूती तलवार घुमाते हुए—'सती मां की जय' के नारे के साथ एच०के०एल० भगत से भिड़े हुए थे। उनके पीछे उनके समधी दिग्विजय सिह भी नंगी तलवार भांज रहे थे। पीछे मध्य प्रदेश के अर्जुन सिह समर्थक इंकाई विधायक तलवार की जगह तख्तियां लिये हुए नारा लगा रहे थे—"मोतीलाल बोरा को बोरे में बंद करो। अर्जुन सिह का कोई चमचा मुख्यमंत्री बनाओ।" भगतजी ने बिना कालर की सफारी गुस्से में उतार कर फेंक दी। वह कच्छा बनियान में आ गये। उन्होंने अर्जुन सिह की तरफ लपकते हुए कहा—"बघेल ठाकुर, यह मेरा असली रूप है। मैं दिल्ली के कच्छा-बनियान अखाड़े का गुरू हूं। तेरी ठकुराई की तो एक मिनट में ऐसी-तैसी कर दूंगा।" इतने में दरबार की ओर से बूटा सिह आक्सफोर्डी चिदम्बरम् की लुंगी खींचते हुए आ गये। बूटा सिंह ने चिदम्बरम को आगे करके कहा, "मद्रासी, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली दरबार में कच्छा-बनियान गिरोह और सती-समर्थक गिरोह में कोई फसाद न होने पाये। बूटा सिह चिदम्बरम को भिड़ा कर दरबार की तरफ 'वाहे गुरू' के स्वर के साथ एफ०आई०आर० दर्ज कराने उलटे पांव लौट लिये। वहां नये इंकाई महामंत्री राम रतन राम पहले से ही एफ०आई०आर० लिखा रहे थे—"सर, जब मैं पिछले दिनों भोपाल इंका विधायकों को आपका अमृत संदेश देने के लिए गया, तो अर्जुन सिह-समर्थकों ने मेरी खाट खड़ी कर दी। बड़ी मुश्किल से जान बची। वे लोग बोरा को तुरन्त मुख्यमंत्री की कुरसी से उठाकर पटक देने पर उतारू थे...।" दिल्ली दरबार ने बीच में बात काटते हुए कहा, "राम रतन राम, तुमने नहीं बताया कि दिल्ली दरबार को एक मिनट का समय इन सब बातों के लिए नहीं है। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रीगन भाई ने डाल दी है। तुम अभी उड़कर जाओ और उनको बताओ कि दिल्ली दरबार के पास बिलकुल समय मुख्यमंत्रियों को बदलने आदि के लिए नहीं है। हमारी इंकाई फौजें इस समय वी०पी० सिह की जनमोर्चा फौजों के साथ बहादुरी के साथ लड़ रही हैं।" दिल्ली दरबार अपनी बात पूरी करें कि उसके पहले बूटा सिंह ने अदब के साथ आगे बढ़कर कान में फुसफुसाना शुरू किया। ज्यों-ज्यों बूटा सिह फुसफुसाते जाते थे, दिल्ली दरबार का चेहरा गुस्से में लाल होता जा रहा था। गुस्से की लाली को और उभारने के लिए जार्ज ने तुरन्त 'लाल बत्ती' की 'स्पाट लाइट' को दिल्ली दरबार के चेहरे पर तेजी से फेंकना शुरू कर दिया। साउंड इफेक्ट के साथ दिल्ली दरबार गुस्से का तांडव करने लगे—"यह क्या शोर मचा रखा है। बंद करो यह बकवास। मुझे इन छोटे-छोटे कामों के लिए कतई फुरसत नहीं है। पूरे मुल्क में एलान कराया जाये कि रीगन भाई ने दिल्ली दरबार को मुल्क के बाहर 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाने के लिए कहा है।" दिल्ली दरबार की सिह गर्जना के बाद पूरे दरबार में गहरी खामोशी छा गयी। अर्जुन सिह ने अपनी राजपूती तलवार बुशर्ट के नीचे छिपा ली और कमर से दोहरे हो गये। कल्पनाथ राय हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। दिल्ली दरबार में 'व्यापक भूमिका' का रीगनी टेप बजने लगा।

—दरबारी लाल

राजीव की नाराजगी

कांग्रेस-इ मुख्यालय में नये महामंत्रियों को मनोनीत करने के बाद राजीव गांधी को ऐसा विश्वास हो चला था कि अब यह नयी टीम प्रभावी ढंग से काम करेगी, लेकिन उनकी निराशा फिर बढ़ने लगी है। पिछले दिनों इंका महामंत्रियों को बुलाकर उन्होंने साफ धमकी दे दी है कि अगर एक निश्चित समय में इंका मुख्यालय के कार्यकलापों में अपेक्षित सुधार नहीं आया, तो वह फिर से महामंत्रियों को बदल सकते हैं।

इंका के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी इस समय अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में भरती हैं। इसलिए उनका काम जी०के० मूपनार को सौंप दिया गया है। मूपनार इंका के शेष महामंत्रियों को अधिक धन नहीं दे रहे हैं। महामंत्रियों के बिलों का अम्बार इंका मुख्यालय के लेखा प्रभाग में लग गया है। ठेकेदार महामंत्रियों पर भुगतान के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन मूपनार का कहना है कि केसरी जी के आने के बाद ही उनके बिल पास होंगे। केवल गुलाम नबी आजाद ही ऐसे महामंत्री हैं, जिनको कुछ रकम अपना काम चलाने के लिए दी जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने इंका मुख्यालय के मुखपत्र 'कांग्रेस वर्णिका' को बंद करने का सुझाव पेश किया था। राजीव गांधी ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब 'कांग्रेस वर्णिका' के स्थान पर एक नया पाक्षिक पत्र निकाला जायेगा। गुलाम नबी 'वर्णिका' के पूरे संपादकीय कर्मियों को हटाकर नये पत्रकार लाना चाहते हैं। कई प्रतिष्ठित पत्रकारों से इस संबंध में सम्पर्क भी स्थापित किया गया है, लेकिन किसी ने अभी तक हां नहीं किया है।

इंका मुख्यालय में पिछले दिनों सबसे अधिक खराब स्थिति महामंत्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी की हुई है। उन्होंने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान बालासाहब देवरस के बयान का जो स्वागत किया था. उसके लिए उनको काफी फटकार मिली। बाद में प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को के०एन० सिंह ने जारी किया जिसमें यह कहा गया, "कांग्रेस को आर०एस०एस० के समर्थन और सहयोग की जरूरत नहीं है।" लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद केदार नाथ सिंह फंस गये। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि त्रिपुरा के होने वाले चुनाव में कांग्रेस त्रिपुरा उपजाति युवा समिति से कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। जैसे ही यह समाचार पत्रों में छपा, संचार राज्यमंत्री सन्तोष मोहन देव ने त्रिपुरा के इन्चार्ज महामंत्री आस्कर फर्नान्डीज को फोन किया, "यह केदार नाथ सिंह ने क्या बयान दे दिया। कांग्रेस और त्रिपुरा उपजाति युवा समिति से चुनावी समझौता तो पिछले सितम्बर में ही हो चुका है।" आस्कर ने जब केदार नाथ सिंह से सम्पर्क किया तो उनका कहना था, "मुझे यह बात नहीं मालूम थी, इसीलिए मैंने बयान दे डाला।" उसके बाद सिंह ने उसका खंडन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया। यह मामला जब राजीव गांधी को बताया गया, तो वह काफी नाराज हुए। राजीव गांधी ने इंका के महामंत्रियों को निर्देश भी दिये कि वे बयानबाजी ज्यादा न करें, लेकिन महामंत्री उससे बाज नहीं आ रहे हैं। राजीव गांधी की नाराजगी बढ़ती जा रही है।

उद्घाटन के बिना उद्घाटन

उत्तर प्रदेश में इन दिनों उद्घाटन समारोहों की बाढ़ आयी हुई है। चाहे किसी कवि सम्मेलन का उद्घाटन हो, किसी कम्पनी के शो रूम का उद्घाटन हो या सुलभ शौचालय के उद्घाटन का कार्य हो, राज्य का हर मंत्री इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए तैयार बैठा रहता है।

ज्यादातर मंत्रियों को शिकायत है कि चूंकि वीर बहादुर ने उन्हें बेकाम कर रखा है, खालीपन न महसूस हो इसलिए किसी भी समारोह के उद्घाटन कार्य का न्योता तत्काल स्वीकार कर लेते है। लेकिन ३१ अक्टूबर को ऐसे ही एक उद्घाटन समारोह का निमंत्रण किसी मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। न तो यह कोई गैर सरकारी समारोह था और न ही, किसी जुआंघर जैसे अवैधानिक कार्यस्थल का उद्घाटन। उद्घाटन समारोह के आयोजकों ने मुख्यमंत्री से लेकर उपमंत्री प्रमिला बधवार मेहरा तक से आग्रह किया, लेकिन हर किसी ने यह कहकर टाल दिया, "न बाबा न, मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगा।"

दरअसल, बात यह थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष १९८२ में गोमती तट पर एक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसकी आधार शिला जिस नेता ने रखी थी, दुर्भाग्य से एक माह में ही वह भगवान को प्यारा हो गया। तब से इस शवदाह गृह का निर्माण लालफीताशाही के हवाले हो गया था। ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसके निर्माण में जमकर कमीशन खाया नतीजतन, इसके तैयार होने में पांच वर्ष से अधिक का समय लग गया और ३२ लाख रुपए खर्च हो गये। इसके तैयार हो जाने पर समस्या यह उठी कि इसका उद्घाटन किस मंत्री से कराया जाय। जिसके पास भी 'आग्रह पत्र' भेजा गया, सबने टाल दिया।

फिर यह तय हुआ कि ३१ अक्टूबर को श्रीमती इन्दिरा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर इसे लखनऊवासियों को समर्पित कर दिया जाये। इस बीच लगभग ५० ऐसे लोगों ने, जिन्हें विकास प्राधिकरण से अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिला था, प्राधिकरण के अधिकारियों को यह लिखकर दिया, "हमारी जमीन सस्ते दामों पर लेकर प्राधिकरण ने आवासीय योजना के तहत ऊंचे दामों पर बेच दी है। हमें अभी तक अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। हम सब, मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। चूंकि हमें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए हमारा आग्रह है कि प्राधिकरण के अधिकारी मुआवजे के कागजातों के साथ ३१ अक्टूबर को हम सबका इस शवदाह में अन्तिम संस्कार कर दें।"

एक साथ ५० उद्घाटन कर्ताओं के मिल जाने के बावजूद प्राधिकरण अधिकारियों ने इसका विधिवत उद्घाटन कराये बिना, इसे लखनऊवासियों को समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश में यह पहला विद्युत शवदाह गृह है।

लाल बक्से का भय

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवाद बहुत गोपनीय होता है। दोनों हर हफ्ते मिलते हैं। फिर तमाम लिखित संवाद एक लाल बक्से में रखे जाते हैं। इस लाल बक्से की चाबी किसी अति उच्च स्तरीय व्यक्ति के पास होती है। इस प्रकार किसी बात के लीक होने की संभावना बहुत कम होती है, पर कभी-कभी हो ही जाता है। मसलन दोनों के बीच संगीत संबंधी पसंद को लेकर पैदा मतभेद। राष्ट्रपति जहां मानते हैं कि सरोदवादक अमजद अली खां नायाब संगीतकार हैं, वहीं प्रधानमंत्री का खयाल है कि कम्प्यूटरी संगीत लाजवाब है। बात यों हुई कि समाचार पूर्व की संकेत धुन बनाने के लिए दूरदर्शन ने अमजद अली खां को ५ लाख रुपए दिये थे, किन्तु अधिकारियों ने उनकी बनायी धुन की जगह पर बंबई स्थित कम्प्यूटरी संगीत को बजाना पसंद किया। इससे बुरी तरह नाराज अमजद अली खां ने राष्ट्रपति से राजीव गांधी से जवाब-तलब करने को कहा। दूरदर्शन के महानिदेशक भाष्कर घोष का कहना था कि उन्हें बंबई स्थित संगीतज्ञ की धुन प्रधानमंत्री की सलाह पर चुननी पड़ी थी। प्रेस तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचे अमजद ने बताया कि राष्ट्रपति दूरदर्शन और प्रधानमंत्री दोनों को 'सबक' सिखायेंगे और आशा है यह लाल बक्से के जरिये होगा। मजे की बात तो यह है कि पसंद की गयी संकेत धुन भी चोरी की बतायी जाती है।

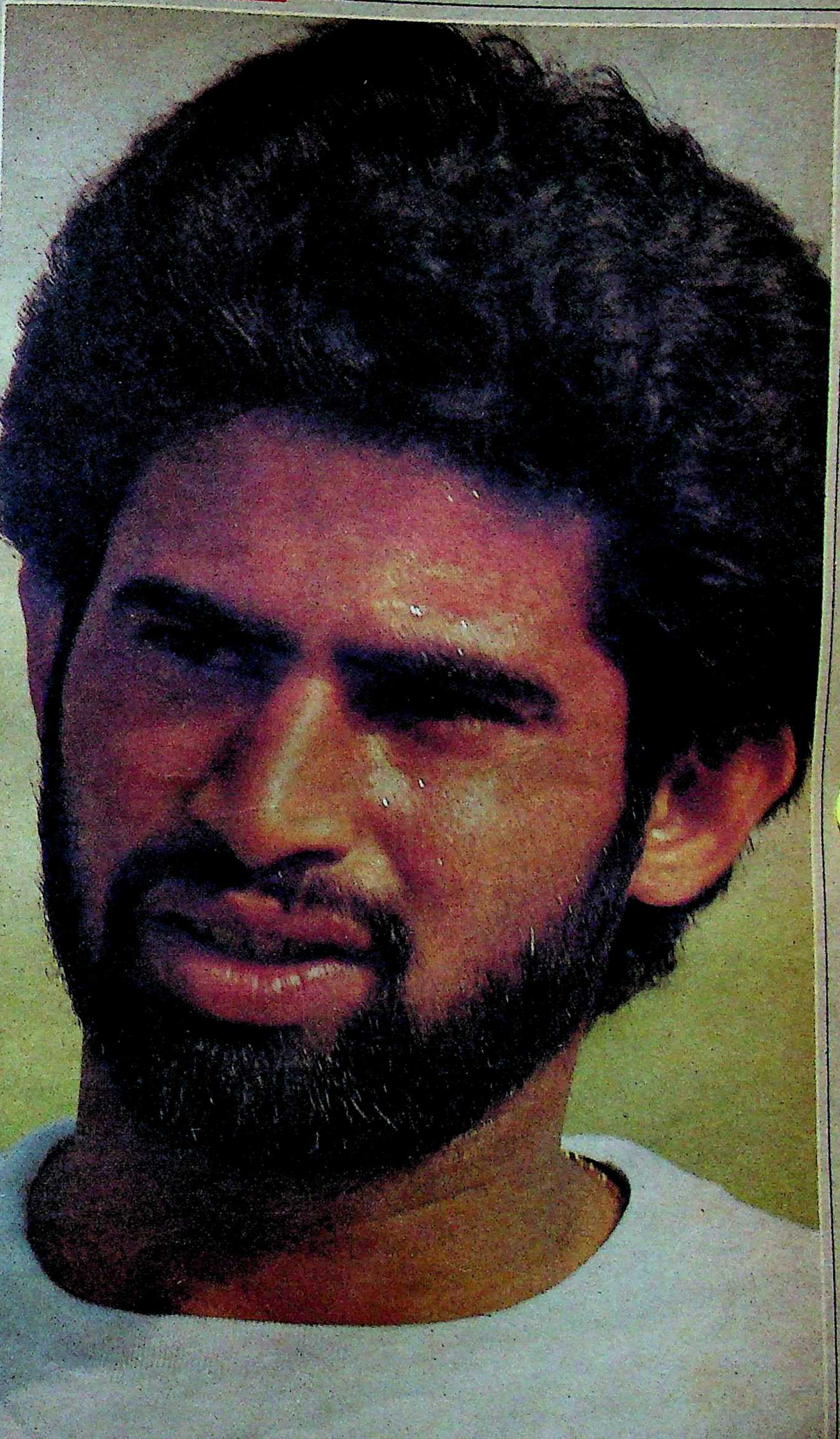

नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेतन शर्मा की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख ही बदल दिया। हरियाणा के इक्कीस वर्षीय इस मध्यम तेज गेंदबाज ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजकर विश्वकप की पहली हैट्रिक बनायी और रिकार्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। चेतन की हैट्रिक के शिकार होने वाले तीन बल्लेबाज थे—केन रदरफोर्ड, इयान स्मिथ और इवान चेटफील्ड। एक दिवसीय मैचों में यह करिश्मा दोहराने वाले वह तीसरे गेंदबाज हैं। इसके पहले पाकिस्तान के जलालुद्दीन और आस्ट्रेलिया के ब्रूस रीड को यह सफलता हासिल हुई थी। १९८३-८४ में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमशेदपुर से अपना क्रिकेट कैरियर शुरू करने वाले चेतन के लिए रिलायंस कप काफी शुभ साबित हुआ है। पहले ही विश्वकप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने एक दिवसीय मैचों में अपने पचास विकेट पूरे किये।

२७ अक्तूबर को राष्ट्रपति आर० वेंकटरमण द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झंडी दिखाने के बाद आठवीं हिमालयन कार रैली का शुभारंभ हुआ। ३००० किलोमीटर की इस कार दौड़ में इस बार सबसे ज्यादा १०६ प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से २० विदेशी थीं। कुल ६६ कारों ने रैली में भाग लिया और निर्धारित समय के अंदर केवल ५४ कारें आखिरी मंजिल तक पहुंचीं।

मित्सुबिशी स्टेरियन कार पर सवार जापान के केनजीरो शिनोजुका और आस्ट्रेलिया के फ्रेड गोसेनटास की जोड़ी शुरू से ही आगे रही और अंत में विजेता होने का सम्मान भी उसे ही मिला। दूसरे स्थान पर आस्ट्रेलिया के रास डकरटन रहे। चार बार के विजेता कीनिया के जयंत शाह को तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा।

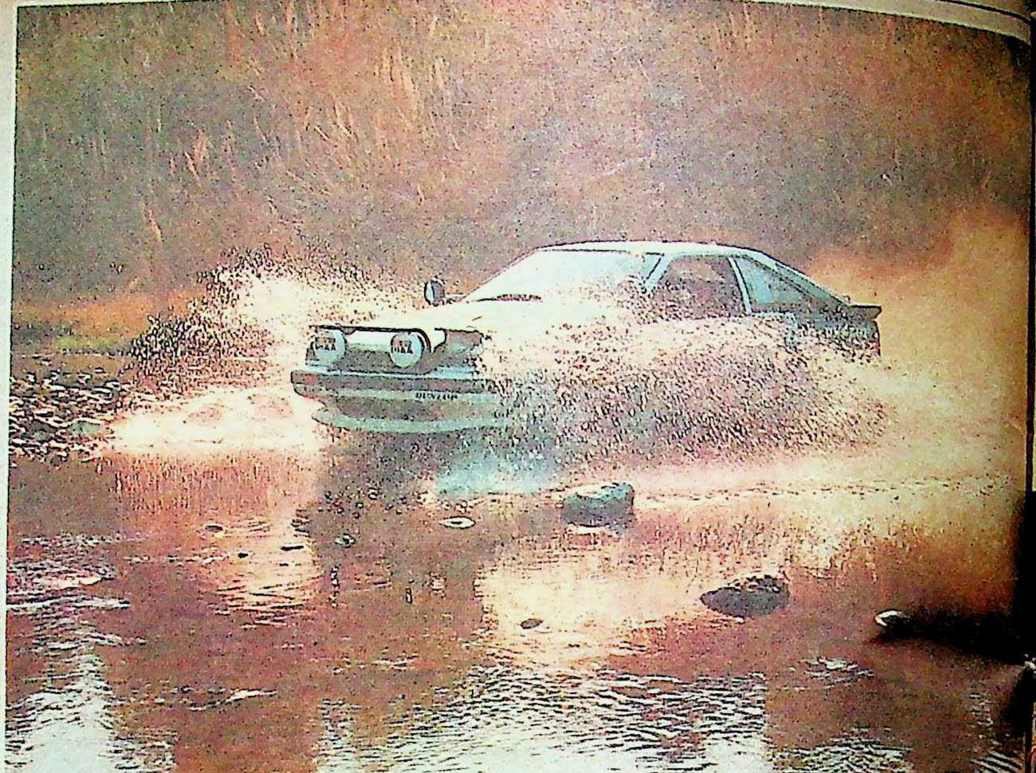

हिमालयन कार रैली, ८७ के पहले चरण में नैनीताल की ओर जा रही एक कार पहाड़ी झरने को पार करती हुई। (ऊपर)

कार्बेट पार्क से गुजरते हुए (बीच में बायें)

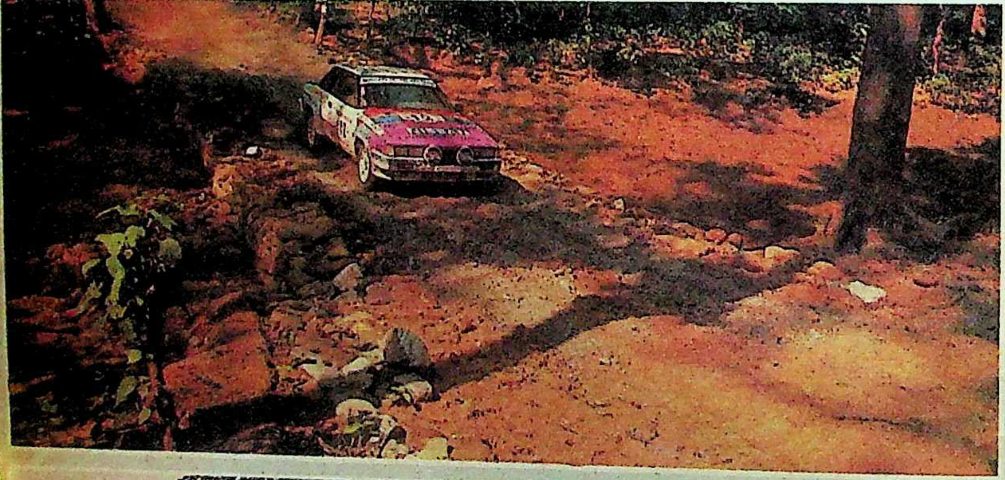

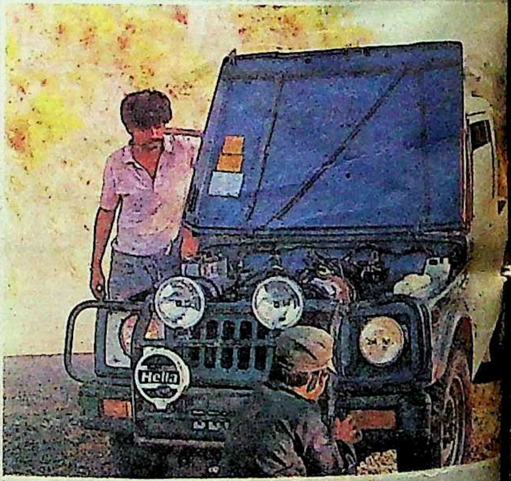

कार रैली के सबसे युवा प्रतियोगी फिरोज मलिक अपनी मारुति जिप्सी के साथ। शिमला जाते हुए उनकी कार में कुछ खराबी आ गयी थी। (बीच में दायें)

मसूरी के टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर एक प्रतियोगी (नीचे)

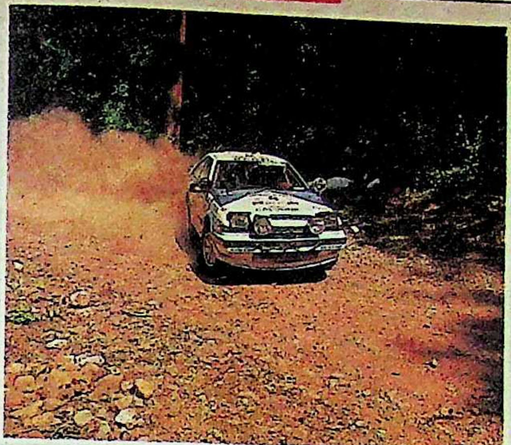

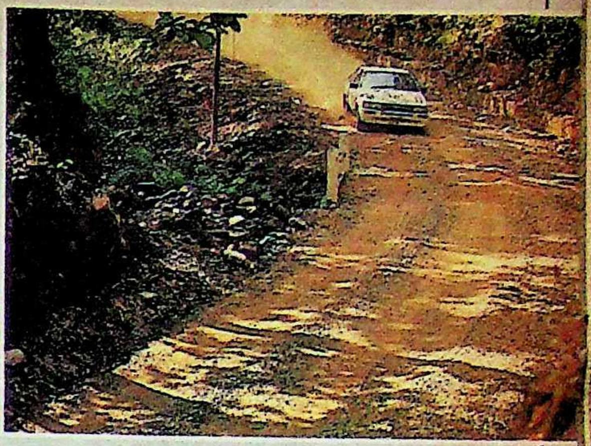

रैली के पहले चरण में धूल भरे मार्ग पर स्पर्धा का सफर (ऊपर बायें)

घने जंगलों के बीच से अपनी मंजिल तय करते हुए (ऊपर दायें)

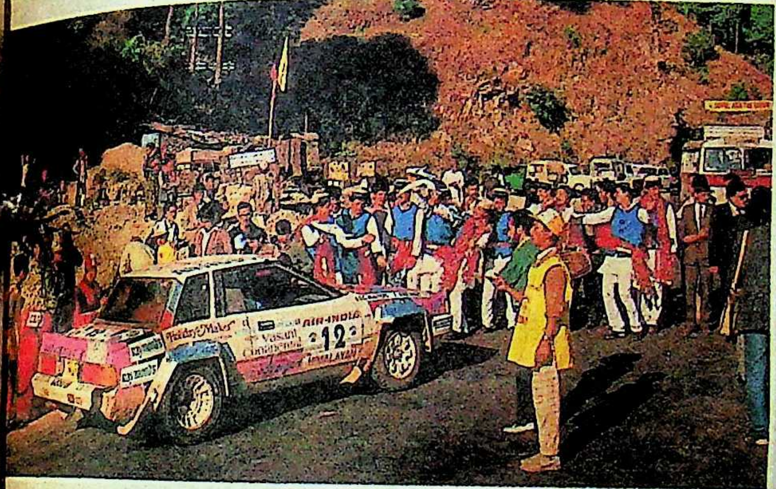

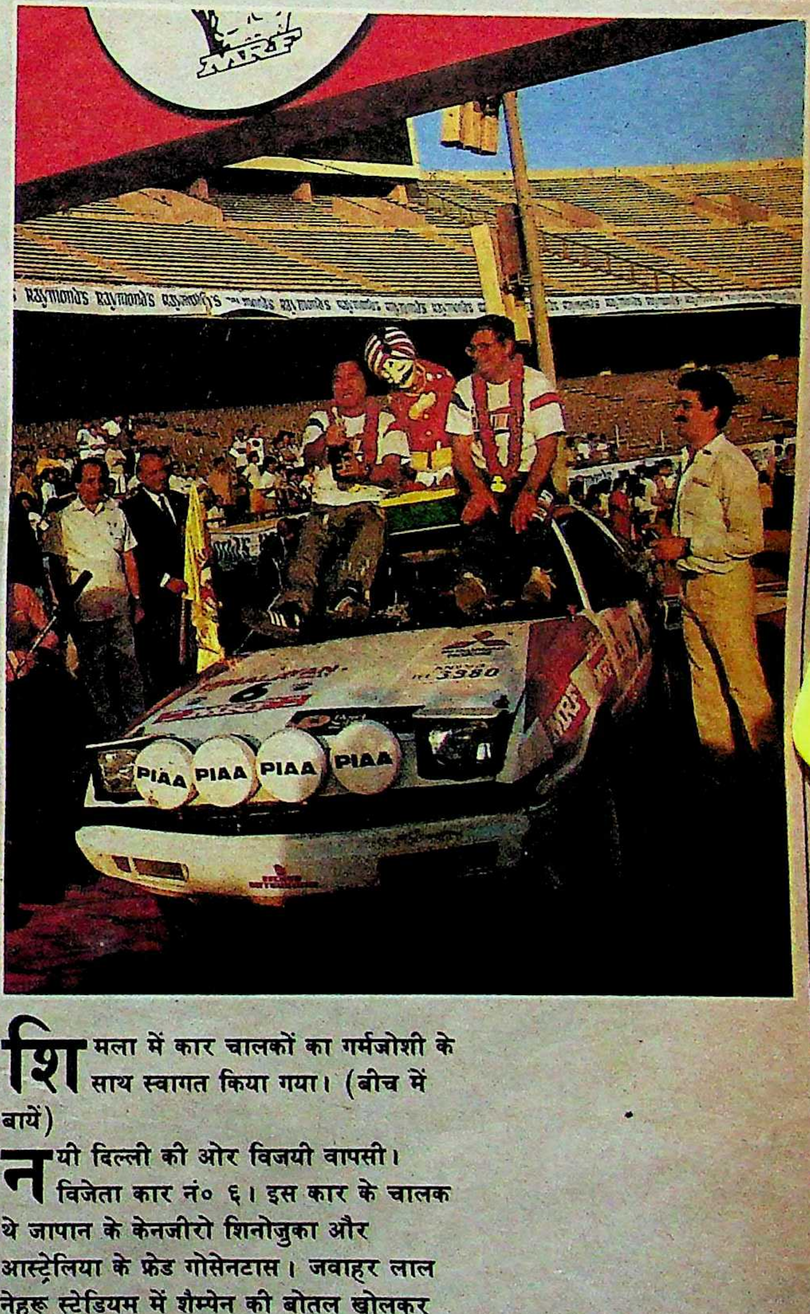
MRF
Raymonds
3380
PIAA
PIAA
PIAA
PIAA

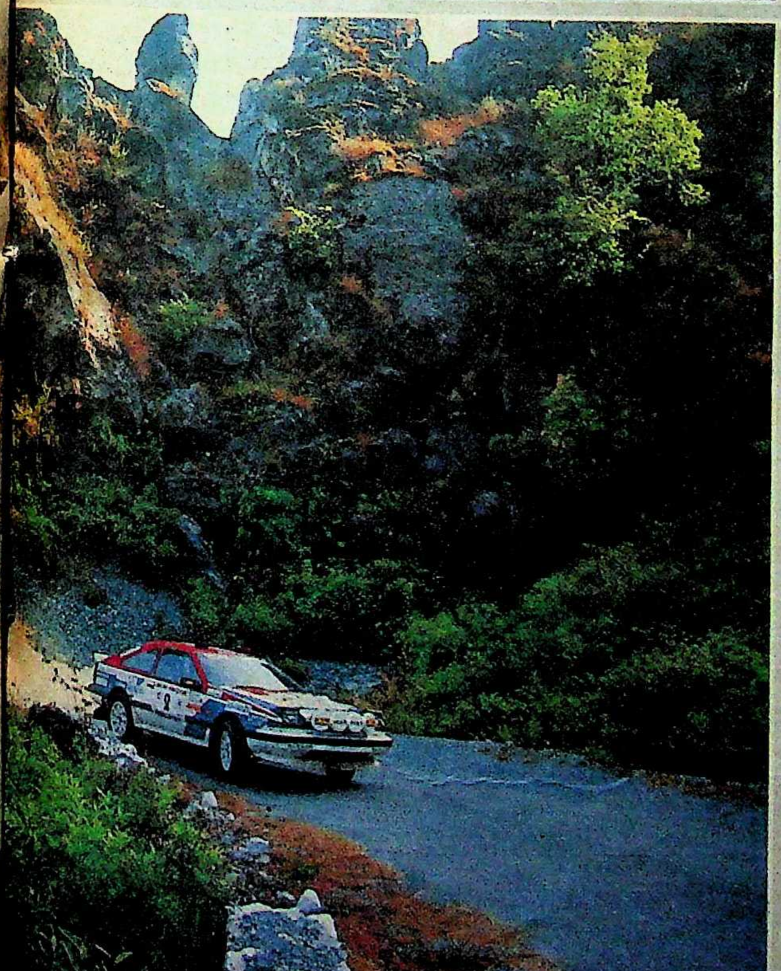

शिमला में कार चालकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। (बीच में बायें)

नयी दिल्ली की ओर विजयी वापसी। विजेता कार नं० ६। इस कार के चालक थे जापान के केनजीरो शिनोजुका और आस्ट्रेलिया के फ्रेड गोसेनटास। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शैम्पेन की बोतल खोलकर जीत का जश्न मनाते हुए दोनों विजेता। (बीच में दायें)

पहाड़ी मार्ग की चुनौती (नीचे बायें)

छाया : रंजन बसु

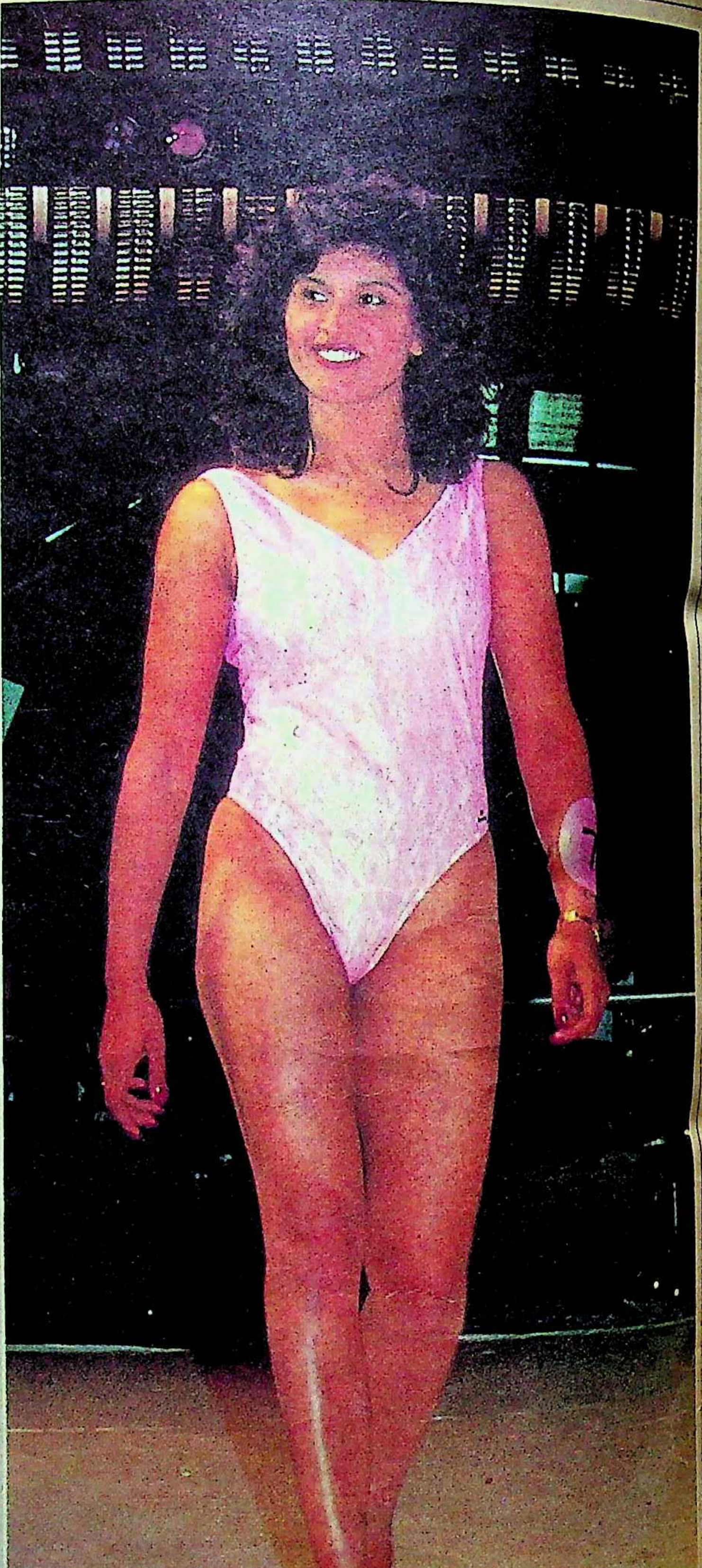

लंदन के हिप्पोड्रोम नाइट क्लब में आयोजित 'मिस एशिया' प्रतियोगिता में थाईलैंड की २० वर्षीया सुंदरी जा ओ (ऊपर) विजयी घोषित हुईं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न एशियाई देशों की २० सुंदरियों ने हिस्सा लिया।

प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली एक भारतीय प्रतियोगी (दायें)

बड़ौदा के राजकुमार

राजतंत्र से लोकतंत्र तक

रियासती वैभव का स्मारक : बड़ौदा का लक्ष्मी विलास महल और फतह सिह राव गायकवाड़ (इनसेट)

१९४७ में भारत से अंग्रेजों के दफा हो जाने के बाद पांच सौ से अधिक छोटी-बड़ी भारतीय रियासतों का भी अंत हो गया था। न राजा रहे और न ही उनके राजसी वैभव, लेकिन बड़ौदा के राजकुमार फतह सिह राव गायकवाड़ ने राजनीति ही नहीं उद्योग के क्षेत्र में भी उतरने की पहल की और अपने लिए एक नये व्यावसायिक साम्राज्य का निर्माण किया। ८१३५ वर्गमील क्षेत्र में फैली बड़ौदा रियासत अपने वैभव के लिए विश्वविख्यात थी और महाराजा को २१ तोपों की सलामी लेने का हक हासिल था। इतनी बड़ी रियासत के वारिस फतह सिह राव गायकवाड़ ने राजशाही का त्याग कर लोकतंत्र में राजनीति और व्यवसाय के क्षेत्र में अपने लिए गरिमामय स्थान बनाने में सफलता कैसे प्राप्त की ?

इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि फतह सिह राव गायकवाड़ को आम आदमी की तरह आचरण करने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि विरासत में मिली सामंती गरिमा को छुपा पाना फिर भी बड़ौदा के इस राजकुमार के लिए मुश्किल हो जाता है। यदि १९४७ में भारत की आजादी के साथ बड़ौदा रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय न हुआ होता, तो राजकुमार फतह सिह गायकवाड़ का जन्म तो शासन करने के लिए ही हुआ था। बंबई के नारिमन पायंट इलाके में स्थित सुरुचिपूर्ण-सज्जित अपने कार्यालय में फतह सिह गायकवाड़ को बैठे देखकर ही सहज अंदाजा लग जाता है कि वह शाही खानदान के हैं, लेकिन यह बता पाना सरल नहीं है कि उनके बारे में ऐसा आभास उनकी किस बात से होता है।

बड़ौदा भारत की संपन्न रियासत रही है, इसका वैभव लोककथा का विषय बन चुका है।

इतनी बड़ी रियासत की क्षति किसी भी व्यक्ति को पागल बना सकती है और फतह सिंह गायकवाड़ तो ९ वर्ष की अवस्था से ही रियासत का कामकाज देखने लगे थे क्योंकि उनके पिता विद्रेश में रहते थे। लेकिन कल के महाराजा ने सामंती जमाने की स्मृतियों को भुलाकर आज बड़ी खूबी से खुद को बंबई की व्यावसायिक दुनिया में आत्मसात कर लिया है।

इस रातो-रात आये बदलाव का कारण बताते हुए वह कहते हैं, "इसका कारण बताना कठिन नहीं है। मैं संक्रमण की संतान हूं। मैंने भवितव्य को वास्तविकता बनने से पहले ही पढ़ लिया था और मैंने इस बात के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि मुझे सिंहासन पर बैठने और राज करने का अवसर नहीं मिलेगा।" शासन करने की उनकी इच्छा और स्वभाव को दिशा और अभिव्यक्ति मिली, उस औद्योगिक साम्राज्य में जिसका उन्होंने बाद में स्वयं निर्माण किया। राजकुमार फतह सिंह गायकवाड़ व्यर्थ की उलझनों में फंस सकते थे, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर सही पथ पर बने रहने का फैसला किया।

ऊहापोह की स्थिति : बहरहाल, अपने अतीत के संबंध में फतह सिंह राव ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। वह कहते हैं, "मैं अतीत की बातों को स्मरण करता हूं लेकिन उन्हें स्मरण न करना बेहतर समझता हूं, क्योंकि अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं होता।" साथ ही अपनी विरासत के प्रति गर्व प्रकट करते हुए वह यह भी कहते हैं, "इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे और उन्हें कैसी निरंकुश सत्ता प्राप्त थी।" फतह सिंह राव का यह कथन यद्यपि यह संकेत देता है कि उन्हें अपने पूर्वजों जैसी सत्ता प्राप्त न होने का खेद है, फिर भी यही एक बात है, जिसका वह खण्डन करते हैं। तथापि उनके प्रपितामह सयाजी राव एक किसान के पुत्र थे जिन्होंने १९३८ तक अपने ६३ वर्षीय शासन के दौरान बड़ौदा रियासत का निर्माण कर उसे वैभवसंपन्न बनाया। उनका देहांत १९३८ में हुआ था। आज भी वह प्रेरणा और गर्व के स्रोत हैं।

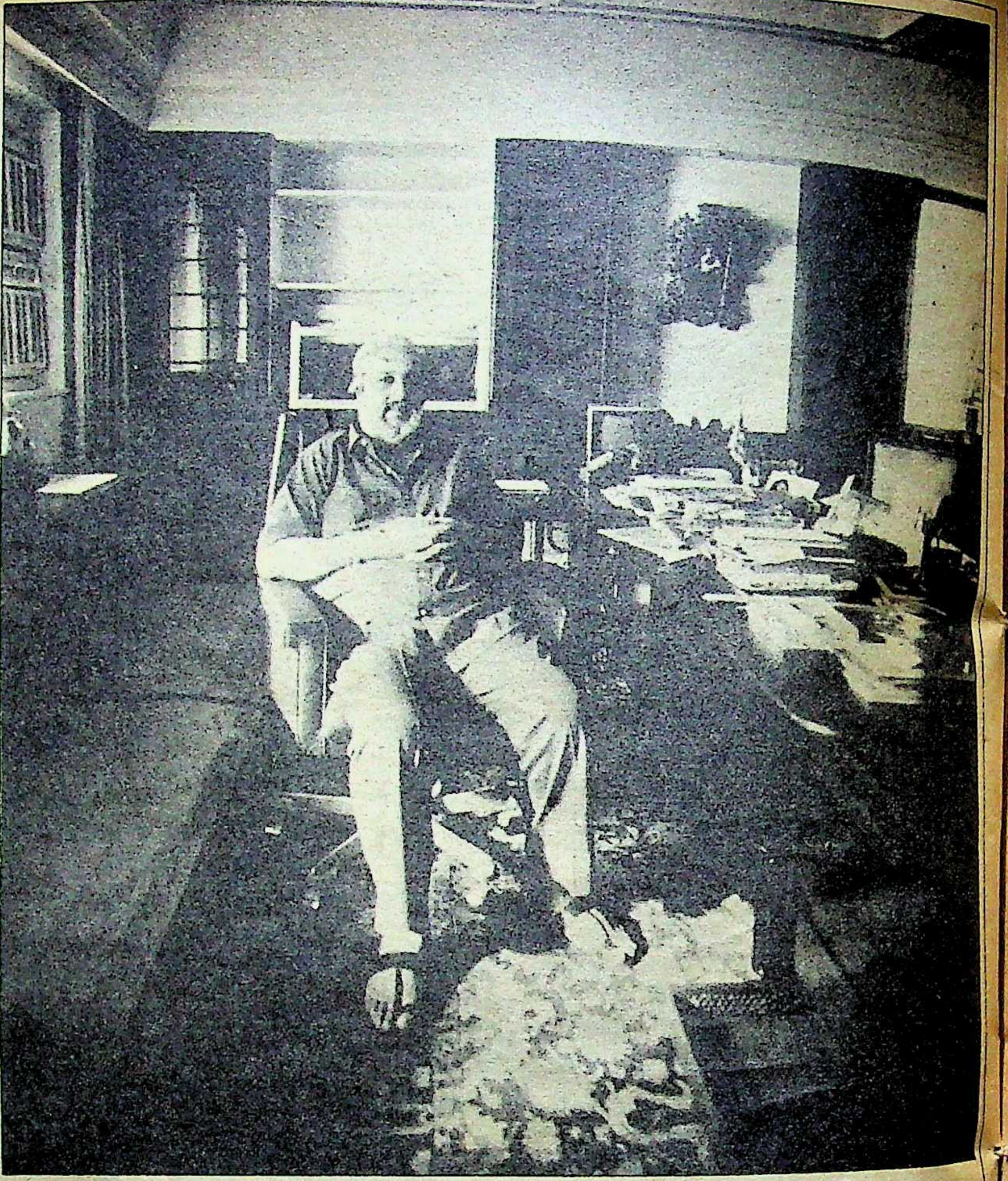

संतोष और शांति : बंबई में अपने कार्यालय में फतह सिंह राव

यह ध्यान देने योग्य है कि अचानक सत्ता मिल जाने से फतह सिंह राव सत्ता के मद में चूर हो सकते थे लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बहुत पहले ही समाज सुधार की पहल की, साक्षरता पर जोर दिया, नारी उद्धार और छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हुए। यह संयोग है कि वह महात्मा गांधी से कभी मिले नहीं, लेकिन उन्हें गांधीजी ने ही सर्वाधिक प्रभावित किया। फतह सिंह बताते हैं, "मेरी चौथी बहन (वह दो भाई और पांच बहनें हैं) और मैंने सात-आठ वर्षों तक सिर्फ बकरी का ही दूध पिया था और राजमहल के प्रांगण में जब मेरी आयु सिर्फ सात वर्ष की थी मैंने खादी पहनना शुरू कर दिया था। उस समय राजमहल के वातावरण में कोई इसकी

व्यावसायिक साम्राज्य : बंबई में १९वीं मंजिल पर अपने बगीचे में फतह सिंह राव

कल्पना तक नहीं कर सकता था। खेद है आजादी की लड़ाई के दौरान मैं एक भी बार महल से बाहर नहीं गया। मैं नहीं समझता कि मुझे ऐसा करने की अनुमति मिलती।''

भव्य महल: इंडो-तुर्क शैली में बना बड़ौदा का लक्ष्मी विलास महल इंग्लैण्ड के राजा के बकिंघम राजमहल से तीन गुना बड़ा है। मुगल शैली के गुंबजों और करारा संगमरमर से सुसज्जित प्रवेश द्वार वाले इस राजमहल में राजकुमार का जीवन उनकी जिम्मेदारियों के बावजूद बड़ा शानदार था। राज्यारोहण समारोह के बारे में फतह सिंह बताते हैं, ''मैं वास्तव में संचालक नहीं था। वह समारोह मेरी मां द्वारा संचालित किया गया था। मैं तो सिर्फ कुछ पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग ले रहा था और धार्मिक संस्कारों को सपन्न करने का कार्य कर रहा था, जबकि किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। उस समय मेरे दिमाग में यह बात आयी थी कि मुझे यह सब जानकारी देना किसी का कर्तव्य था, लेकिन इससे मेरी इच्छा और आनंद में कोई कमी नहीं आयी थी। मुझे वह सब पसंद था, और मैं चाहता था कि ये समारोह जितनी देर तक चलता, उतना ही अच्छा होता।''

रियासत की बागडोर संभालने की तैयारी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एक अंग्रेज शिक्षक ने उन्हें लिखना-पढ़ना तो सिखाया ही, साथ ही उनके अंदर साहित्य और काव्य के प्रति रुचि भी जागृत की। यद्यपि वह अपने शिक्षक को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्हें याद है कि राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने अंग्रेज शिक्षक को यहां तक कह दिया था, ''आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके, यह देश छोड़कर चले जायें।''

शिक्षा: कठोर अनुशासन में रहते हुए उन्होंने अपनी पढाई जारी रखी और सीनियर कैंब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह कैंब्रिज के पेट्स कालेज में शिक्षा ग्रहण करें। वहां उनका दाखिला हुआ भी, लेकिन वहां वह केवल दस दिनों तक ही रहे। अंग्रेजों से उनके पिता का विवाद हो जाने के कारण उन्हें वापस बुला लिया गया। बस यहीं से उनकी औपचारिक शिक्षा का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा स्वयं को शिक्षित करने का जो सिलसिला शुरू किया, वह आज भी जारी है। उच्च कोटि की पुस्तकों का बार-बार अध्ययन करते रहना उनकी ऐसी आदत बन गयी, जिसका अकसर उनके मित्र मजाक भी उड़ाते हैं। वह अपनी परिचित मुस्कान के साथ बताते हैं, ''मैं अपने छात्रों को कहता हूं कि मैं सर्वाधिक अनपढ़ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उन सबसे ज्यादा जानता हूं।''

कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं, जिनसे उनके विद्रोही स्वभाव का पता चलता है। परंपरा से चले आ रहे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उनके मन में अनेक सवाल उठा करते थे। उनका कहना है, ''असल समस्या यह थी कि मैं बहुत से सवाल पूछा करता था, जिनका उत्तर न तो पंडित और न ही मेरे परिवार के सदस्य

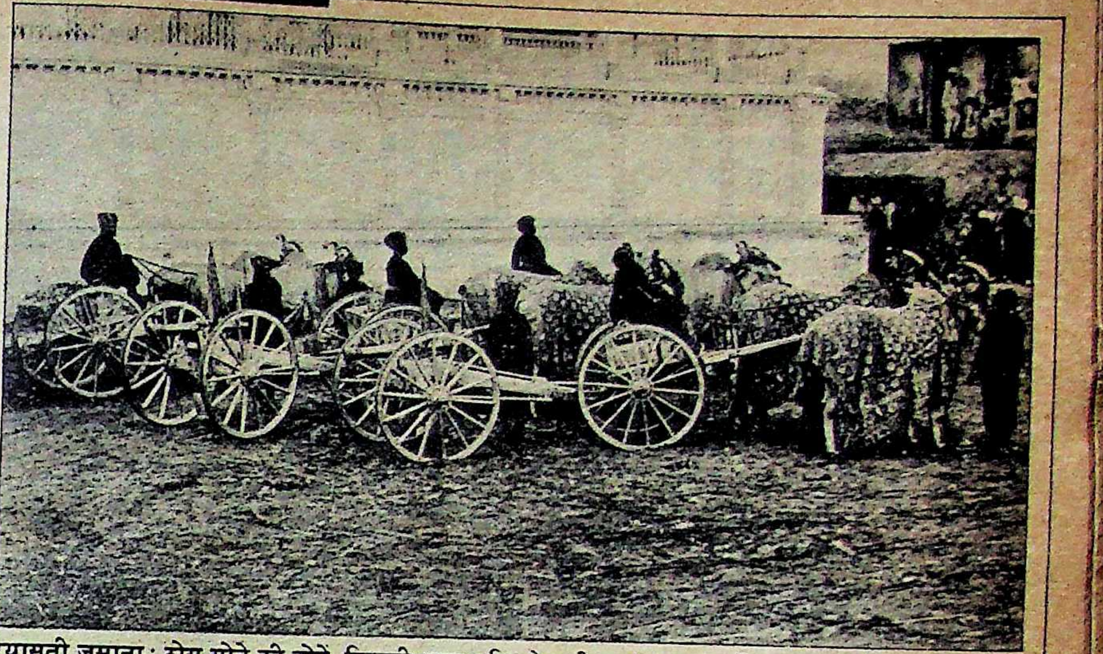

रियासती जमाना: ठोस सोने की तोपें, जिनकी आज प्रति तोप कीमत ४१.२० करोड़ रुपए होगी

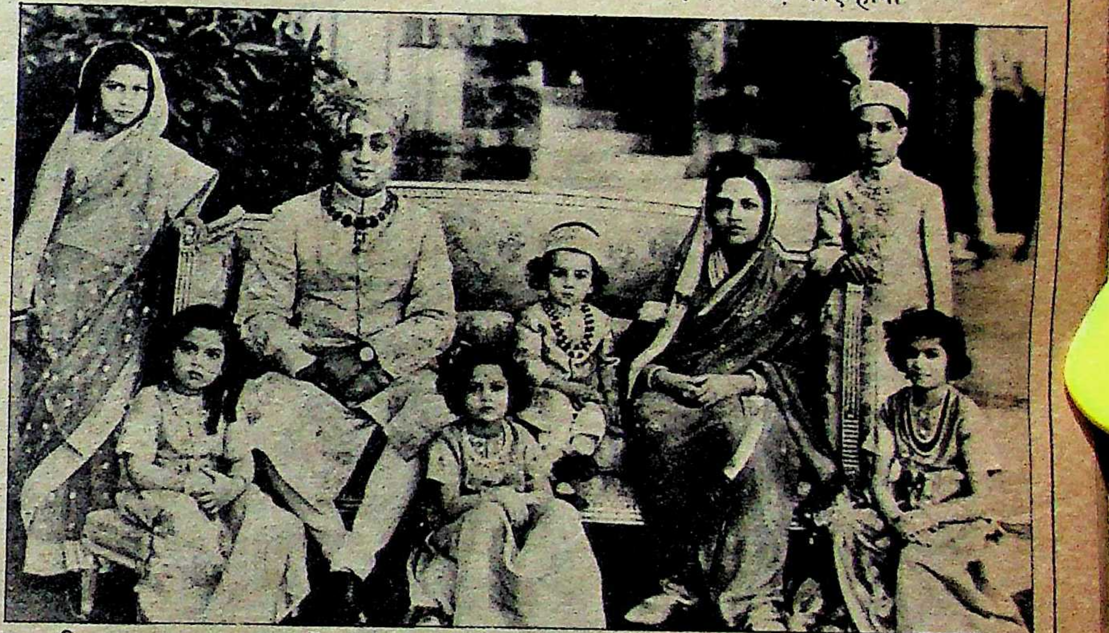

राज परिवार: महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ और महारानी शांता देवी, राजकुमार फतह सिंह राव (दायें खड़े हुए), राजकुमार रंजीत सिंह और चारों राजकुमारियां

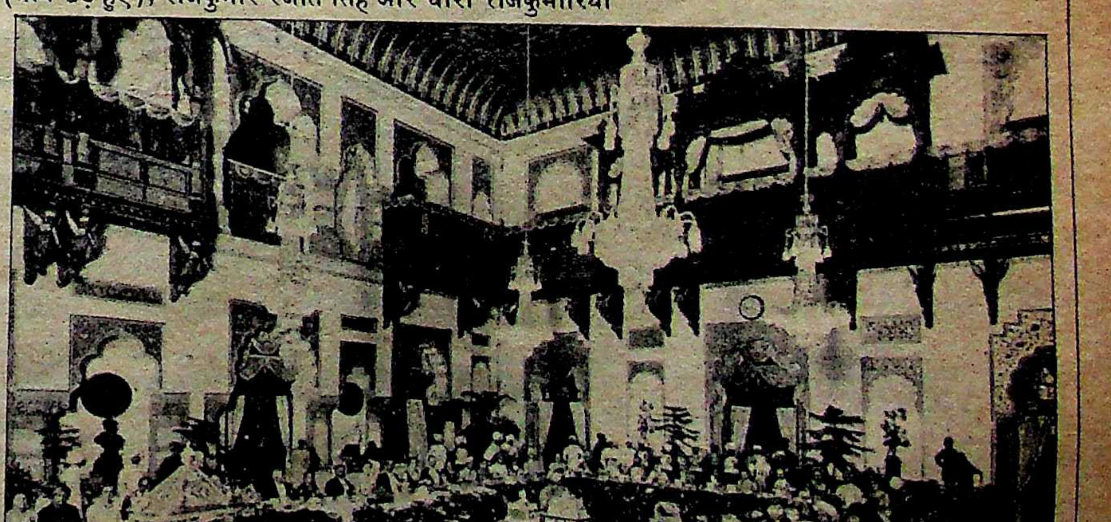

शाही दावत का एक दृश्य

आज आप वो काम कर सकते हैं जो दर्शाए कि आपको परिवार का कितना ख्याल है।

अपनी धर्मपत्नी के लिए आप पति ही नहीं उसका संसार हैं। आपके ही भरोसे उसका संसार सुखी है। आपके बच्चों के सपने भी आपकी बदौलत ही साकार होते हैं।

एक कार्य करके आप उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए कितने चिन्तित हैं, बता सकते हैं।

युनाइटेड इण्डिया की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी—वो कार्य, जो आपकी हज़ारों भावनाओं का दूसरा नाम होगा।

आज, हर एक के लिए दुर्घटनाओं का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसे में उन खतरों के प्रति अपनी सुरक्षा का कुछ प्रबन्ध करना अक्लमंदी होगा! अपने स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए जिनकी दुनिया आपके ही चारों तरफ घूमती है।

युनाइटेड इण्डिया की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी ज़रूरत के वक्त आपकी मदद करती है। यदि दुर्घटना हो जाए तो यह अस्थायी व स्थायी अपंगता के लिए मुआवज़ा देती है। एक सीमा तक चिकित्सा खर्च का भी भुगतान करती है। इससे भी कहीं ज्यादा, दुर्घटना से लगे सदमें से फौरन सम्हलने में भी आपकी सहायता करती है।

युनाइटेड इण्डिया में हम, लोगों और उनकी ज़रूरतों को सही तौर पर समझते हैं। आप उद्योगपति हों या भूमिहीन मज़दूर, फैक्टरी में काम करने वाले हों या मुर्गी पालक कृषक, जहाजों के मालिक हों या ताड़ी खींचने वाले—हम तो देशभर में बिखरे अपने ९१५ शाखाओं के माध्यम से सभी के पास पहुंचना चाहते हैं। उनकी विशेष ज़रूरतों के अनुसार पॉलिसियां बनाना चाहते हैं और उनके दावों को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं।

जी हां, जब तक जोखिम हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम हैं—युनाइटेड इण्डिया।

UNITED INDIA

युनाइटेड इण्डिया इन्श्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारतीय साधारण बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी)
२४, व्हाइट्स रोड, मद्रास-६०० ०१४।

हर दिन, हर पल हम आपके साथ रहेंगे।

Mudra: M: UI: 3522 Hin

दे पाते थे। उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता था। तब से मुझे नास्तिक कहा जाने लगा, जबकि आज भी मैं वैसा ही हूं।''

एक अवसर पर तो उनका मूड जो खराब हुआ, तो उसे ठीक होने में तीन साल लग गये। वह बताते हैं, ''जोधपुर की राजकुमारी से अपनी सगाई की बात मैंने रेडियो पर सुनी थी। मुझे किसी ने सूचित करने की भी जरूरत नहीं समझी, सब कुछ अपने आप तय कर दिया। १६ वर्ष की अवस्था में मेरी कुछ और योजनाएं थीं, जैसे क्रिकेट खेलना, कैंब्रिज जाना और इन बातों को दरकिनार कर लोगों ने मुझसे यह आशा की कि मैं सब कुछ खुशी-खुशी स्वीकार कर लूंगा।'' इनके इस विवाह से इनकार कर देने से इनके पिता काफी कुपित हुए। अंततः तीन सालों की समझाइश के बाद फतह सिंह कुछ ढीले पड़े और एक वर्ष बाद २० वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गयी।

शादी का समारोह और कार्यक्रम, रियासती गौरव के अनुरूप जोधपुर और बड़ौदा दोनों जगहों में लगभग एक महीने तक चलता रहा। बारात में लगभग ४००० लोग थे। सब कुछ तो खुशी-खुशी बीत गया, लेकिन अपव्यय बहुत हुआ। उसी का परिणाम है कि ऐसी शादियों में जिनमें व्यर्थ का खर्च होता है, फतह सिंह आज भी शामिल नहीं होते। वह बताते हैं, ''मैं अपनी भांजियों और भतीजों से कहता हूं कि यदि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा यह चाचा तुम लोगों की शादियों में शामिल हो तो वे सादगी के साथ विधिवत शादियां करें। मैं अपने भाइयों और बहनों को यह भी सलाह देता हूं कि वे अपने से छोटों के लिए शेयर या संपत्ति खरीदने के अवसरों पर ही धन खर्च करें।''

औद्योगिक साम्राज्य: उन्होंने अपने जिस औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण किया, उसमें भी उनकी इसी व्यवहारकुशलता के दर्शन होते हैं। इसने बड़ौदा रियासत के विलय के कारण हुई आर्थिक क्षति की न केवल पूर्ति की, बल्कि उन्हें शांति भी दी। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से १९५५ में बड़ौदा रेयन की शुरुआत की, जिसका उन्हें लाभ भी मिला। वह कहते हैं, ''१९४७ में प्रिवीपर्स की रकम २२ लाख रुपए सलाना निर्धारित हुई थी, लेकिन १९५१ में इसमें कटौती करके इसे १० लाख कर दिया गया। इस कमी को पूरा करने के लिए समारोहों के खर्चों में कटौती की गयी, जिसे जनता ने पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे पास सीमित विकल्प थे।''

बड़ौदा रेयन ने फतह सिंह गायकवाड़ को

फतह सिंह और क्रिकेट

फतह सिंह राव को क्रिकेट का शौक बचपन से ही रहा है और यह शौक उनमें आज भी मौजूद है। उन्होंने महल के प्रांगण में खजूर की लकड़ी से बने बैट और दीवाल पर स्टम्प बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उनके नौकर-चाकर ही गेंदबाज और क्षेत्ररक्षक के रूप में तब उनके सक्रिय सहयोगी थे। आज भी फतह सिंह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न समितियों के सदस्य हैं। वह रिलायंस कप बोर्ड के भी सदस्य हैं। जब वह २९ वर्ष के थे, तभी उन्हें १९५९ में पाकिस्तान जाने वाली भारतीय टीम का मैनेजर नियुक्त होने का सम्मान प्राप्त हुआ। अंतिम बार १९८२-८३ में भी वह भारतीय टीम के मैनेजर रहे। केवल क्रिकेट ही ऐसा खेल है, जिसके बारे में वह अधिकार-पूर्वक अपना विचार व्यक्त करते हैं। यहां क्रिकेट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार प्रस्तुत हैं:

खेल में हुए परिवर्तनों के बारे में: धन को अहमियत मिलने के कारण अब क्रिकेट में बहुत बदलाव आ गया है। भौतिकवादी संसार में शायद यह आवश्यक भी हो, तो भी मैं किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। क्रिकेट अब टीम भावना का खेल नहीं रह गया है जैसा कि अब तक मैं समझता था। अब हर खिलाड़ी अपने लिए खेलता है और अंततोगत्वा उसका प्रभाव पूरे खेल पर पड़ता है। यह परिवर्तन रातों-रात नहीं आया है, बल्कि विगत १५-२० सालों में धीरे-धीरे आया है।

व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता: मेरी समझ में तो भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में प्रेस कहीं अधिक दोषी है, जिसने बिना सिर-पैर की बातें छापी हैं। बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर की प्रतिद्वंद्विता की बातें जितनी अतिशयोक्ति के साथ छापी गयीं, उतनी ही आज कपिल और सुनील के बारे में भी छप रही हैं।

एक दिवसीय क्रिकेट: इसे तो मैं क्रिकेट मानता ही नहीं। यह तो मूलतः पैसा कमाने का धंधा है। १९८७ में तो दिन ढलते-ढलते एक दिवसीय क्रिकेट के परिणाम सामने आ जाते हैं। लेकिन यह क्रिकेट को बर्बाद भी कर रहा है और विश्वभर के क्रिकेट खिलाड़ियों में से आज बहुत से क्रिकेट खिलाड़ी, विशेषकर बल्लेबाज इसके कारण ही बर्बाद हो चुके हैं। वे जिस प्रकार का स्ट्रोक लगाते हैं, उसका अस्तित्व तो क्रिकेट की पुस्तकों में भी नहीं है। आज तो पूरा नजरिया ही बदल गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि हरेक ने अब इसे स्वीकार भी कर लिया है।

विगत ३० सालों के सर्वोत्तम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में: मैं अपने समय के अच्छे-से-अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेला और उन्हें देखा, लेकिन सुनील गावस्कर की तरह कोई नहीं मिला। वही एक पूर्ण क्रिकेट खिलाड़ी है जो खेल को समझता है, जबकि आज के बहुत सारे खिलाड़ियों में इस समझ का अभाव है। सुनील के विकल्प की खोज करना अब अत्यंत कठिन होगा।

भारतीय टीम के बारे में: हमारे समय में कुछ ही अच्छे खिलाड़ी होते थे, लेकिन पूरी-की-पूरी टीम अच्छी नहीं कही जा सकती थी। शारीरिक अक्षमता हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी रही। आज भी जो भारत की ओर से खेल रहे हैं, वे अच्छे बल्लेबाज या गेंदबाज तो हैं लेकिन उनका क्षेत्ररक्षण ठीक नहीं है। वे झुक नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। इसीलिए ५० रनों तक पहुंचते-पहुंचते वे चुक जाते हैं। मौजूदा भारतीयं टीम बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि पाकिस्तानी टीम है।

भारत में प्रतिभाओं के अभाव पर: प्रतिभाओं की खोज हमारी प्रमुख समस्याओं में से एक है। प्रतिभाओं को खोजकर भी हम उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए कुछ नहीं कर पाते। पाकिस्तान, अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करता है। उसके अधिकांश खिलाड़ी इंग्लैंड में क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

पाकिस्तान के दौरे पर जानेवाली टीम के बार-बार मैनेजर नियुक्त होने पर: मैं नहीं जानता कि मुझे बार-बार क्यों मैनेज़र बनाया गया? उन लोगों ने शायद यह सोचकर ऐसा किया हो कि मैं संकट की स्थिति में भी टीम को संभाल लेने की क्षमता रखता हूं। भारत-पाक शृंखला ने ऐतिहासिक कारणों से सदैव तनाव पैदा किया है, लेकिन हम लोगों के सामने कभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं आयी।

१९७८ के पाकिस्तान दौरे पर जाते समय एक समस्या मेरे सामने आयी थी, लेकिन वह समस्या भारत-पाक शृंखला से संबंधित न होकर पैकर टेस्ट शृंखला से सबंधित थी, जिसे सुलझाने के लिए वाक़ई मुझे कूटनीति से काम लेना पड़ा। मेरे पास रोजाना प्रेस की कतरनें भेजी जातीं, जिनमें तरह-तरह की अफवाहें होतीं। एक दिन, मैंने उन कतरनों को अपनी टीम के पास भेजा और एक मीटिंग बुलायी। उसके पहले ही, मैंने बिशन सिंह बेदी, जो कि भारतीय टीम के कप्तान थे, को बुलाया। जब मैंने उन्हें समाचार कतरनों का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि हमारे नौ खिलाड़ी पैकर टेस्ट शृंखला में खेलने के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं तो उन्होंने कहा, ''चिंता न करें, सर, कुछ नहीं होगा।'' तब मैंने सुनील को बुलाया, उसने कहा, ''मैं अपने देश को कभी नीचा देखने नहीं दूंगा।'' तब मैं समझ गया कि अब कोई समस्या नहीं रह गयी है और हमारी टीम का कोई खिलाड़ी पैकर में नहीं गया।

—रंजना कक्कड़

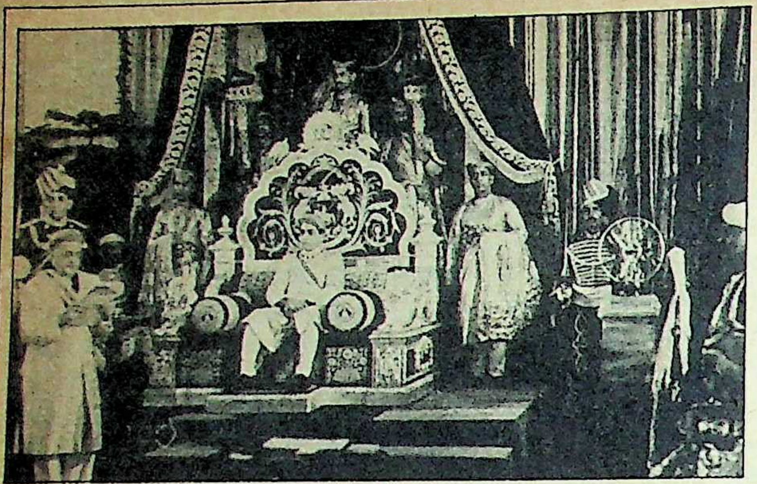

फतह सिंह राव के पिता महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ का दरबार

शिकारी से वन्य जीवों के संरक्षक : पालतू कछुओं के साथ फतह सिंह राव

रियासती राजकुमारों का मार्गदर्शक बना दिया। तब तक ये राजकुमार मुख्यत: किसी उद्योग में धन लगाते थे या किसी कंपनी के निदेशक बनते थे। लेकिन फतह सिंह ने पहली बार किसी उद्योग की स्थापना की और सफलतापूर्वक उसका नियंत्रण और संचालन करके दिखा दिया। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने तब एक उद्योग को शुरू करने की पहल की। उनका कहना है, "विभिन्न कायदे-कानूनों की रुकावटों के कारण आज किसी उद्योग को शुरू करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है।"

लेकिन व्यावसायिक कार्यों की देखभाल करने के लिए उन्हें अपनी सल्तनत बड़ौदा से बंबई स्थानांतरित करनी पड़ी। अब वही उनका मुख्यालय है। जब वह भारत में होते हैं, तो अपना अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते हैं। विदेश भ्रमण में अभी भी उनकी बेहद रुचि है। लक्ष्मी विलास पैलेस उनके लिए अब महज घर सरीखा है, जहां वह साल भर में मुश्किल से एक मास ठहरते हैं। महल की विशालता का वर्णन करते हुए वह अकसर कहते हैं कि भोजनकक्ष से शयनकक्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें स्कूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है—यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह सच है कि अब यह महल वैसा नहीं रह गया है, जैसाकि अतीत के अच्छे दिनों में था।

बेहाल महल: महल के बगीचे की अब देखभाल नहीं होती। इसी तरह तांबे के विशालकाय बैल की प्रतिमा भी बढ़ी हुई घास के बीच उपेक्षित पड़ी है। क्रिकेट का मैदान उपेक्षित है, अब उसमें टेनिस कोर्ट बना दिया गया है। कभी महल के बरामदों में सफेद पायजामों और गहरे नीले रंग की जाकेटों की वर्दी पहने सुरक्षाकर्मी खड़े रहते थे—आज वह खाली पड़ा है। ६०० निजी सेवकों की फौज भी अब घटकर १५० रह गयी है। ये समर्पित सेवक हैं और वे सिर्फ इसलिए वहां हैं, क्योंकि फतह सिंह उन सबकी देखभाल करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया है। उनका कहना है, "यदि मुझे कुछ हो जाये, तो भी मुझे इनकी चिंता नहीं। मैंने किसी को अपने से अलग नहीं किया। अधिकांश पुराने सेवकों को अपनी कंपनियों में मैंने नौकरी द दी है।" उनकी कारों के क्लीनर, मैकेनिक आदि भी समय के गर्त में चले गये हैं, फिर भी महल में २० कारें अभी भी विद्यमान हैं और रियासती तौर-तरीके भी। हाथी दांत की बनी स्फटिक धवल कुर्सियों और रत्नजड़ित मेजों की अभी भी नियमित सफायी होती है और वे प्रयोग में लायी जाती हैं। हीरे-मोती जड़ी कालीनें तो अब वहां नहीं हैं फिर भी फारस की अनेक बेशकीमती कालीनें वहां जरूर हैं। अभी भी चांदी की विशाल चायदानी से चाय दी जाती है और ट्रे बेलफास्ट की बनी शानदार झालर से ढकी रहती है। विक्टोरिया जमाने के लैम्पों से अभी भी दीवारों पर सज्जित चित्र प्रकाशित होते हैं, जबकि महोगनी लकड़ी की बनी आलमारियां नाज़ुक वेनेशियन ग्लास और ड्रेसडन के बने बर्तनों से भरी पड़ी हैं। बहरहाल, महल का रखरखाव अब दुष्कर होता जा रहा है। फतह सिंह को इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में महल को विकसित और परिरक्षित करने के लिए राजीव गांधी रुचि ले रहे हैं। प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिए बनी 'इनटच' (आई०एन०टी०ए०सी०एच०) न्यास से मदद लेने की बातचीत चल रही है। लेकिन फतह सिंह को कुल गौरव के प्रति अपने स्नेह को बनाये रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं।

फतह सिंह राव जब भी राजमहल आते हैं, तो उनके सेवकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं और उनके सामने अपनी छोटी-बड़ी समस्याएं रखते हैं। फतह सिंह बताते हैं, "मैं एक अच्छा श्रोता हूं, मैं उनकी बातें सुनता हूं, इसलिए लोग आते हैं।" इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं कि यद्यपि अधिकांश लोगों के लिए मैं फतह सिंह राव हूं, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा महाराजा ही मानते हैं।" यह कहने की आवश्यकता नहीं कि फतह सिंह राव को ऐसे लोगों की मदद करने में आनंद आता है। उनका कहना है, "मेरे पास जो कुछ है, वह सब जनता का है।"

राजनीति में: जनता से मिले इसी असीम स्नेह और आदर के कारण फतह सिंह १९५६ में राजनीति में आये। वह बताते हैं, "मैंने जनता से कहा कि यदि आप चाहते हैं तो मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। यह फैसला करके मैं पंडित नेहरू के पास गया, तो पंडितजी ने कहा कि जब आपने अपना मन बना लिया है, तो मुझसे पूछने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा, 'मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं।' पंडितजी ने तब कहा था कि मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। पंडितजी वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छे थे।" इस प्रकार फतह सिंह राजनीति में आये और २४ वर्षों तक वह राजनीति में रहे। उन्होंने छह चुनाव लड़े, और १९८० में राजनीति से अलग हो गये। इस दौरान वह तत्कालीन सुरक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के संसदीय सचिव रहे। १९६२ के भारत-चीन युद्ध के समय भी वह उनके संसदीय सचिव थे। चार वर्षों तक वह गुजरात में राज्य मंत्री भी रहे। बहरहाल कृष्णा मेनन के संबंध में चर्चा छेड़ने पर वह बड़ी कूटनीति से इस विषय को 'सरकारी गोपनीयता' कहते हुए टाल जाते हैं। इस समय जो राजनीति देश में चल रही है, उससे यह कट्टर देशभक्त बहुत दुखी है। वह बड़ी पीड़ा से कहते हैं, "हमने निश्चित रूप से देश को वर्तमान असंगठित स्थिति तक पहुंचाने के लिए तो कुर्बानी नहीं दी थी।"

शिकारी से संरक्षक: एक समय के शिकारी रहे फतह सिंह राव का समय और शक्ति इन दिनों वन्य जीवों के संरक्षण में लग रही है। वह 'विश्व वन्य जीव कोष' के अध्यक्ष हैं। वह कहते हैं, "अब व्यवसाय मेरे लिए गौण हो गया है और वन्य-जीव संरक्षण प्रमुख।" वह बताते हैं कि उनमें यह बदलाव अचानक आया। अफ्रीका के जंगलों में वह वन्य जीवों का शिकार करने गये थे। वह बंदूक और कैमरा दोनों से शूट कर रहे थे, तभी उन्हें यह आत्मज्ञान हुआ कि किसी जीव को बंदूक से मार देने के बाद उसका अस्तित्व फिर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसे कैमरे से शूट किया जाता है, वह अस्तित्वमान रहता है और उसे कैमरे से बार-बार शूट किया जा सकता है। यह ज्ञान होते ही मैंने बंदूक हमेशा-हमेशा के लिए त्याग दी।"

बड़ौदा के भूतपूर्व महाराजा फतह सिंह राव एक लेखक भी हैं। भारत के राजमहलों पर उनकी एक पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी है। उनके प्रपितामह

की जीवनी करीब-करीब तैयार है। लेकिन लोगों को स्वयं फतह सिंह राव की आत्मकथा का इंतजार है। उनकी मां इसे लिखने पर काफी जोर दे रही हैं और स्वयं फतह सिंह राव भी उत्सुक हैं। देखना है, वह उसमें कितनी, कौन सी जानकारियां व किस्से देते हैं तथा किन धारणाओं का खण्डन करते हैं। फतह सिंह के बारे में एक धारणा तो यही बनी हुई है कि उन्हें विरासत में मिली संपदा से बेहद लगाव है, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। यह सुनकर वह ठहाका लगाते हुए कहते हैं, "मैं समझता हूं कि यह धारणा एक पत्रिका द्वारा मेरे बारे में यह लिखने पर फैली कि मैं विश्व के दस सर्वाधिक अमीर लोगों में से एक हूं। मैंने उस पत्रिका के संवादाता को कहा था कि तुमने मेरे बारे में गलत लिखा है, जबकि लिखना यह चाहिए था कि मैं दुनिया के दस सबसे बड़े मूर्खों या ईमानदार लोगों में से एक हूं, क्योंकि जब मैं अपनी संपत्ति की घोषणा करता हूं तो ईमानदारी से करता हूं। आज मेरी अधिकांश संपत्ति, उसी संपत्ति पर लगे कर को चुकाने में समाप्त हो चुकी है।"

संपदा का मिथक: बड़ौदा रियासत की संपदा हमेशा से उत्सुकता और जनरुचि का विषय रही है। हैदराबाद के बाद बड़ौदा ही वह रियासत है, जिसके कीमती शानदार आभूषणों की चर्चा दुनिया भर में रही है। इस राजघराने के पास रंगीन हीरे से जड़ित वह हार था, जिसे नेपोलियन ने भेंटस्वरूप दिया था। सात लड़ियों का मोतियों का हार तो विख्यात था ही। बड़ौदा में बना मोतियों का एक कालीन मदीना में मोहम्मद साहब की मजार पर चढ़ाया गया था। रियासती जमाने में २८० पौण्ड की खालिस सोने की तोपें राजमहल के सामने चमकती रहती थीं। शाही दंपती सफेद बैलों द्वारा सज्जित जिस बैलगाड़ी में बैठकर शहर में निकलते थे, वह ठोस सोने और चांदी से बनी होती थी। यहां तक कि हाथियों को भी सोने के नूपुर पहनाये जाते थे। अब वह जमाना नहीं रहा। बड़ौदा रियासत का यह सारा वैभव अब गुजरे जमाने की बातें हो चुका है।

अब एकांतप्रिय: एक समय जेट रफ्तार से जिंदगी जीनेवाले फतह सिंह अब एकांतप्रिय होते जा रहे हैं। उनका कहना है, "पाल गैटी (अमरीका का एकांतवासी लखपति) की तरह तो नहीं, लेकिन मैं अब निरंतर एकांतप्रेमी होता जा रहा हूं।" यह कथन उस व्यक्ति में आये बदलाव का संकेत देता है जिसने सार्वजनिक रूप से इकबाल किया है कि 'एक समय ऐसा क्या था जो मैंने नहीं किया।' फतह सिंह का कहना है, "लेकिन हर व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वह सब व्यर्थ था, लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी तो वे सारे काम करने जरूरी थे। जिसका आपने अनुभव नहीं किया है, या जिसे आपने नहीं अपनाया, उसका त्याग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।"

अब उनकी आयु ५७ वर्ष की हो चुकी है, फिलहाल स्वास्थ्य नरम है। उन्होंने प्रचुर यश अर्जित किया है, जिसने उन्हें सौम्य बना दिया है, लेकिन इससे उनकी यह इच्छा और बलवती हुई है, "वही करूं जो मैं करना चाहता हूं।" बहरहाल, वह इस मिथक को भी तोड़ते हैं कि 'शासक अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है'। उनका कहना है, "मुझे कई दबावों के आगे झुकना पड़ा। तीन वर्ष पूर्व जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, तो मुझे यह सलाह तक दी गयी थी कि मैं पुनर्विवाह कर लूं। लेकिन महज विवाह के लिए एक महिला को रखने का इच्छुक मैं नहीं हूं। मैं अपना आदमी स्वयं बनना चाहता हूं।" फतह सिंह को यह विचार पसंद नहीं कि जब वह घर लौटें, तो कोई उन्हें डार्लिंग कहे और सिनेमा जाने के लिए कहे, जबकि उनकी इच्छा घर पर बैठने की हो।

फतह सिंह ने कर्मठ जीवन जिया है। आज भी वह सुबह आठ से शाम के आठ बजे तक काम करते हैं। उसके बाद वह वन्य-जीवन (उनके पास अच्छा संग्रह है) पर बनी वीडियो फिल्में देखते हैं या अमजद या शुजात (जो उन्हें डैडी कहकर पुकारते हैं) के संगीत में डूबे रहते हैं। उनके इस प्रकार के रहन-सहन को देखते हुए उनके इष्टमित्र उनका सम्मान भी करते हैं। आजकल वह अपना अधिकतर समय अपने कछुओं की देखभाल करने में व्यतीत करते हैं। उनका पालन-पोषण तो करते ही हैं उनका मासिक रिकार्ड भी रखते हैं। अजीब सा लगता है! क्या वह पहचानते भी हैं?" इसके उत्तर में जब वह कहते हैं, 'हां' तो हर किसी को इस पर विश्वास करना पड़ता है।

—रंजना कक्कड़

जोड़ों की जकड़न से उसका
चलना-फिरना मुहाल क्यों हो?

जब गुणकारी शक्ति
आपके हाथ में हो.

आपके स्नेहसिक्त हाथों की प्यार भरी गर्मी और आयोडेक्स की गुणकारी शक्ति – यही तो चाहिए उसको.

इसलिए आयोडेक्स हमेशा पास में रखिए. क्योंकि आयोडेक्स में है चोट खायी कोशिकाओं को अच्छा करनेवाला आयोडिन और दर्द दूर करनेवाला मिथाईल सैलिसिलेट.

आयोडेक्स रोजाना दो बार मलें तो दुगना फायदा मिले

डाक्टरों की सलाह है कि जब तक दर्द जाये नहीं आयोडेक्स रोजाना दो बार मलिए... बल्कि और भी कुछ दिनों तक. क्योंकि दर्द तो केवल बाहरी इशारा है, असली कारण तो है कोशिकाओं की भीतरी चोट.

इसलिए जब भी आपके किसी प्रिय को जोड़ों की जकड़न, मोच, पेशियों में खिंचाव, या बदन दर्द की शिकायत हो तो आयोडेक्स मलिए. रोजाना दो बार. फिर तो वे आपका गुण गायेंगे और दुगनी तेजी से काम पर चले आयेंगे.

SKOF—एसकेएफ का उत्पादन.

आयोडेक्स®
गुणकारी शक्ति से भरपूर खास बाम

ELL-1510

दावणगेरे

फ़ैशन फ़ैब्रिक्स

नर्म-मुलायम बनावट वाले
प्रिया और प्रेमिका टेरीन * साड़ियां
—मनमोहक डिज़ाइनों में.
हर एक की पसंद के अनुरूप
अनेकों खूबसूरत, लुभावने
रंगों में.

साथ ही उपलब्ध

- सूटिंग्स • शर्टिंग्स
- ड्रेस मटीरियल्स
- कैम्ब्रिक
- टू × टू रूबिया
- टर्किश टॉवेल्स

* टेरीन काफ़ी का ट्रेडमार्क है

T/9788/6/HIN

दि दावणगेरे कॉटन मिल्स लिमिटेड
हनुमानथप्पा बिल्डिंग्स, चित्रदुर्गा रोड, दावणगेरे-५७७ ००२.
शोरूम: कावेरी भवन, बंगलौर-५६० ००९. दाजीबन पेठ, हुबली-५८० ०२०. चित्रदुर्गा रोड, दावणगेरे-५७७ ००२.

वामपंथियों का खेल

भारतीय वामपंथियों के बारे में यह मसल मशहूर है कि जब बारिश रूस में होती है, तो ये यहां छाता खोल लेते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान १९४२ में ब्रिटिश सरकार के खेमे में रहने और फिर १९६२ में चीनी हमले को 'हमला' न करार देने, बल्कि चीन का परोक्ष समर्थन करने के कारण 'देशद्रोही, विश्वासघाती' आदि फतवों का भारतीय वामपंथियों के नाम से जुड़ जाना, न आश्चर्यजनक था न अनपेक्षित। आश्चर्यजनक तो उनका अपने इस इतिहास से इस हद तक ऊपर उठना है कि आज वे देश के वर्तमान राजनीतिक रंगमंच पर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं जो महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अंततः निर्णायक भी सिद्ध हो सकती है। इस राजनीतिक फासले को तय करने के लिये उन्होने क्या रणनीति अपनायी? क्या-सचमुच ही कम्युनिस्टों ने तिकड़मों और बैसाखियों का सहारा लिया? क्या सत्ता हथियाना, भले ही मार्ग कोई भी हो, उनका प्रमुख ध्येय बन गया है?

वामपंथी-रीति-नीति की सफलता का ज्वलंत उदाहरण प० बंगाल के जाने-माने मुख्यमंत्री ज्योति बसु हैं। श्री बसु ने तीसरी बार प० बंगाल के मुख्यमंत्री चुने जाने का रिकार्ड तो स्थापित किया ही, साथ ही उनकी उज्ज्वल व्यक्तिगत छवि और प्रशासनिक दक्षता ने उन्हें भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और कुशल मुख्यमंत्री की उपाधि भी प्रदान की है।

७५ वर्षीय गौरवर्णीय, सुदर्शन, मृदुभाषी और दिल का दौरा झेले हुए ज्योति बसु में अभी भी युवा जैसी चुस्ती और महत्वाकांक्षा विद्यमान है। किन्तु गौरतलब बात यह है कि यह सब उन्हें मार्क्सवादी सिद्धांतों से न प्राप्त होकर भारतीय राजनीतिक अनिवार्यताओं से मिला है। इन्हीं अनिवार्यताओं को पहचानकर श्री बसु के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने जो नीति-परिवर्तन समय-समय पर किये, उसने यदि एक ओर आशातीत सफलता प्रदान की, तो दूसरी ओर उसके स्वरूप में इतना अधिक रद्दोबदल किया है कि आज पार्टी की क्रांतिकारी छवि मद्धिम पड़ गयी है और उसके स्थान पर सुधारवादी स्वरूप उभर आया है। जिसने न केवल वामपंथियों को ऊहापोह की स्थिति में डाला है, बल्कि उन्हें विविध आरोपों का सामना भी करना पड़ा है।

सशस्त्र क्रांति: स्वतंत्रता के बाद साम्यवादियों के शुरुआती तेवर क्रांतिकारी थे। फरवरी, १९४८ में अपने द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के दौरान उन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा नेहरू सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर तेलंगाना (आंध्र प्रदेश) में संघर्ष का बिगुल बजा दिया था। इसके तहत उन्होंने भूमिहीनों एवं निर्धन वर्ग को हथियारबंद कर भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा जमींदारों के सफाये के लिये 'सर्वहारा का युद्ध'

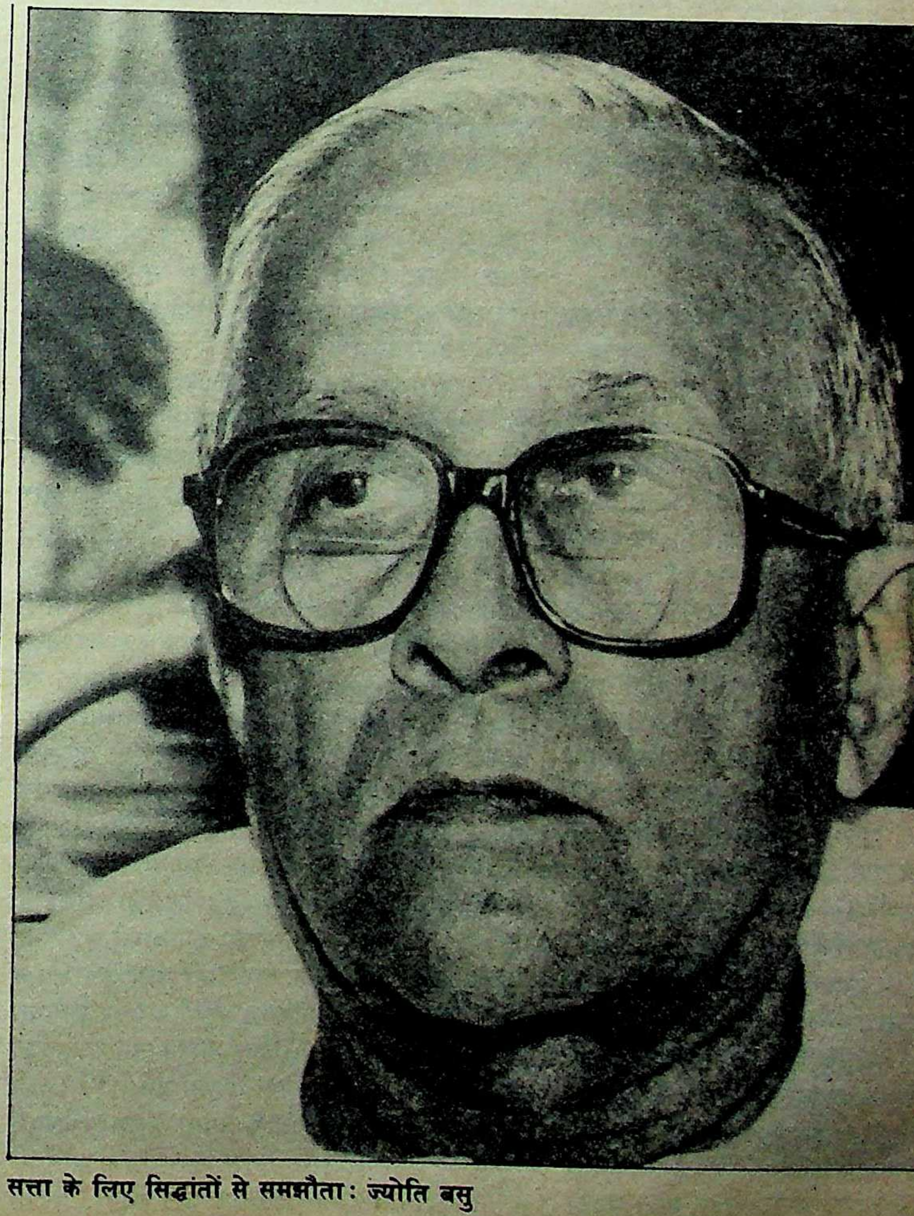

सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता: ज्योति बसु

राजीव का समर्थन भी, विरोध भी : नंबूदिरीपाद

रूसपरस्ती : राजेश्वर राव

आरंभ किया। फलस्वरूप पुलिस-जमींदारों से उनकी हुई मुठभेड़ों में सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ी और बुरी तरह मुंह की खाने के बाद कम्युनिस्टों का सशस्त्र क्रांति का स्वप्न चकनाचूर हो गया। अपरिपक्व अभियान चलाने के बाद रूस से डांट पड़ी सो अलग।

इस प्रारंभिक शिकस्त ने कम्युनिस्टों को यह गूढ़ सबक सिखाया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सशस्त्र क्रांति असंभव है। पार्टी के सुधारवादी स्वरूप की नींव इसी कारण पड़ी। १९५२ में प्रथम आम चुनाव में भाग लेने का निर्णय इसी का द्योतक था। १९५७ के केरल विधानसभा चुनाव में प्राप्त विजय ने उनके इरादों को इतना सशक्त बना दिया कि दो वर्ष पश्चात पदच्युत किये जाने पर भी न तो वे हतोत्साहित हुए न ही उन्होंने चुनाव द्वारा सत्ता हासिल करने का मार्ग बदला।

किंतु एक अन्य झटका कम्युनिस्टों को लगभग तोड़ने-समाप्त करने में सफल हो गया। १९६२ में हुए भारत पर चीनी हमले ने समस्त भारतीय-कम्युनिस्टों की वफादारी और भूमिका पर एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया। पार्टी के भीतर भी पारस्परिक वैचारिक द्वन्द्व कुछ कम न था। विवादग्रस्त आंतरिक स्थिति के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में चीन और रूस के मध्य चल रहे विवादों के फलस्वरूप 'क्रांतिकारियों और सुधारवादियों के दो भिन्न गुट उभरे। १९६४ के तेनाली अधिवेशन में दल का विभाजन हो गया, जिसमें दल के क्रांतिकारी गुट ने चीन के माओत्सेतुंग को अपना नेता स्वीकारते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को जन्म दिया। यह विभाजन न सिर्फ पार्टी और आंदोलन दोनों को ही बहुत महंगा पड़ा, बल्कि देश के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका व्यापक और दूरगामी प्रभाव रहा। विपक्ष के एक वामपंथी झुकाव वाले अनुभवी नेता के अनुसार—"यदि भारतीय कम्युनिस्टों में यह विभाजन न हुआ होता, तो आज देश को विपक्ष के लिए तरसना न पड़ता और एक सशक्त, लोकतांत्रिक विपक्ष कांग्रेस को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार होता।"

विभाजन ने दोनों कम्युनिस्ट गुटों को भिन्न-भिन्न मार्ग पर डाल दिया, यद्यपि मूल उद्देश्य एक ही था। कालांतर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 'कुमारमंगलम थीसिस' के तहत ऊपर से क्रांति लाने के लिए कांग्रेस में घुसपैठ का निर्णय लिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। समय अनुकूल था, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस का विभाजन कर अल्पसंख्यक सरकार चला रही थीं। उन्हें कम्युनिस्टों के सहयोग-सहायता की उतनी ही आवश्यकता थी, जितनी कम्युनिस्टों को अपना क्षेत्र व्यापक करने की और जिसकी सफलता की आशा उन्हें एक 'कमजोर' श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से पूरी तरह थी। यही कारण है कि भाकपा ने श्रीमती गांधी का साथ इमरजेंसी में भी दिया। दुर्भाग्यवश परिणाम विपरीत हुआ। जैसा कि भाजपा के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं, "कोई भी सत्ता-समर्थक पार्टी, जो स्वयं सत्तारूढ़ न हो, अपने नेताओं को महत्वपूर्ण स्थान, हैसियत आदि तो दिला देती है, किंतु उसका जनाधार सदा के लिए और निश्चित रूप से घट जाता है।" हुआ भी यही। कांग्रेस के सहारे अपना आधार विस्तृत करने की जगह भाकपा अपना रहा-सहा आधार भी खोती गयी। पार्टी में असंतोष और विवाद इतना अधिक बढ़ा कि एक बार उसमें फिर विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप पार्टी अध्यक्ष श्रीपाद अमृत डांगे अपनी एक अलग पार्टी अ०भा० कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण कर बैठे। यद्यपि उनके साथ भाकपा के इक्कादुक्का नेता और मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही गये, किंतु कमजोर होती भाकपा के लिए यह एक जबर्दस्त आघात तो था ही।

ज्योति बसु और नम्बूदिरीपाद के नेतृत्व वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति का मार्ग न छोड़ने और सत्तारूढ़ दल से पृथक रहने के निश्चय पर अडिग रही। किंतु समस्या यह थी कि लोकतांत्रिक ढांचे में किस प्रकार अपना वर्चस्व कायम कर जनाधार विस्तृत किया जाये? १९६७ के चुनाव में वह मैदान में उतरी और उसमें प्राप्त सफलता के कारण न केवल उसे आंदोलन का नेतृत्व प्राप्त हुआ, बल्कि केरल और प० बंगाल में विपक्ष का सबसे बड़ा गुट होने और सत्तारूढ़ होने की प्रबल कामना ने माकपा को सिद्धांतो को ताक पर रखने को विवश किया। माकपा ने दोनों जगह न केवल तिरस्कृत सुधारवादी कम्युनिस्ट, बल्कि अन्य बुजुआ दलों के साथ मिलकर मोर्चा सरकारें बनायीं। फलस्वरूप यदि एक ओर पार्टी सत्तारूढ़ हो गयी, तो दूसरी ओर पार्टी का 'क्रांतिकारी' हिस्सा, जिसका विश्वास था कि सत्ता बंदूक से हासिल की जाती है, जेहाद का ऐलान कर, चीन का वरदहस्त पाकर अलग हो गया—मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के नाम से। बाद में यही भाग नक्सलवादी भी कहलाया।

कांग्रेस के सहारे अपना आधार विस्तृत करने की जगह भाकपा अपना रहा-सहा आधार भी खोती गयी। पार्टी में असंतोष और विवाद इतना अधिक बढ़ा कि एक बार उसमें फिर विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप पार्टी अध्यक्ष श्रीपाद अमृत डांगे अपनी एक अलग पार्टी अ०भा० कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण कर बैठे। यद्यपि उनके साथ भाकपा के इक्का-दुक्का नेता और मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही गये, किंतु कमजोर होती भाकपा के लिए यह एक जबर्दस्त आघात तो था ही।

त्रिपुरा में जमे हैं: नृपेन चक्रवर्ती

दोनों जगह पदच्युत किये जाने पर सन ७० से ७७ तक माकपा को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ शंकर राय की अगुवाई में कांग्रेस ने प० बंगाल में कहर बरसाया, जिसमें नक्सलवादियों का लगभग सफाया हो गया। इमरजेंसी में कठिनाइयों की पराकाष्ठा में भी माकपा को कांग्रेस और श्रीमती गांधी के समर्थन का लोभ नहीं सताया। फलस्वरूप १९७७ में जेपी के कंधे पर सवार हो कर जनता लहर में पार्टी ने अपने दो प्रमुख गढ़ों—प० बंगाल और त्रिपुरा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। तब से लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में माकपा लगी हुई है। देश में चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलन में तो बड़े भाई की भूमिका निभा ही रही है, साथ ही विपक्ष के मध्य उसने अपना एक विशिष्ट स्थान भी बना लिया है। आज भीमकाय कांग्रेस के बाद तीन विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ होने का सौभाग्य मात्र माकपा को ही प्राप्त है।

समझौते : किंतु इस गौरव को प्राप्त करने के लिए किये गये विभिन्न सैद्धांतिक व राजनीतिक समझौतों ने माकपा के ध्येय और कार्यप्रणाली दोनों को ही कटघरे में उसी प्रकार ला खड़ा किया है, जिस प्रकार सत्ता का पल्लू पकड़ने और पैंतरे बदलने पर भाकपा को। दोनों कम्युनिस्ट दलों पर मौकापरस्ती और सत्ता हथियाने के प्रयास के आरोपों की बौछार भी कुछ कम नहीं है।

यह सत्य है कि तमाम समझौते चुनाव की अनिवार्यताओं के तहत ही किये गये हैं जो प्राय: दिशा-परिवर्तन के लिये बाध्य करते हैं। विपक्ष और कांग्रेस दोनों ही कम्युनिस्टों को इस मामले में बख्शने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी धारणा है कि कम्युनिस्टों ने हमेशा दोमुंही नीति अपनायी है। वह भी सिद्धांतों का गला घोंटकर। प० बंगाल में माकपा से सीधा युद्ध छेड़ने वाले कांग्रेसी नेता प्रियरंजन दासमुंशी के अनुसार, "भारतीय राजनीति में कम्युनिस्टों ने कभी भी समान नीति नहीं अपनायी है।" इसका समर्थन करते हुए जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुपदस्वामी कहते हैं, "कम्युनिस्टों का इतिहास दोमुंही नीतियों से भरा है। अंतर्विरोध उनकी रणनीति का अभिन्न अंग है। उनकी भाषा में थीसिस और एंटीथीसिस का समन्वय है। राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और लक्ष्यों के लिये उन्होंने कभी भी समान नीति नहीं अपनायी है।" एक अन्य कांग्रेसी नेता ने सवाल किया, "क्या गिरगिट जैसे रंग बदलना, ढुलमुलपन, कम्युनिस्टों की विशेष और अनोखी अदा है?"

विभिन्न आरोपों-आक्षेपों पर 'माया' से विस्तार से चर्चा करते हुए दासमुंशी ने कहा कि कम्युनिस्टों के पास चार सैद्धांतिक मुद्दे हैं, जिनका समय समय पर उन्होंने मखौल उड़ाया और समझौते किये हैं। कम्युनिस्टों का सर्वप्रथम मुद्दा है—जनता को आर्थिक शोषण से मुक्त करना। किंतु इससे संन्यास उन्होंने तभी ले लिया, जब उन्होंने १९६७ से लगातार ऐसे दलों व तत्वों से गठबंधन किया जो इसके बिलकुल विपरीत राजाओं, इजारेदारों और आर्थिक विषमताओं के पोषक थे। १९७७ में दक्षिणपंथी जनता पार्टी के साथ भरत मिलाप कर उन्होंने अपनी रही सही इज्जत और सिद्धांतों को धूलधूसरित कर दिया। कम्युनिस्टों का दूसरा नारा है उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी तत्वों के खिलाफ संघर्ष। दासमुंशी के अनुसार प० बंगाल में सत्तारूढ़ होने के बाद वामपंथियों ने बहुराष्ट्रीय निगमों को खुली दावत देकर अपनी कथनी और करनी का अंतर स्वयं उजागर कर दिया। कम्युनिस्टों का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भूमि सुधार का था। कुछ हद तक उन्होंने इस पर किये अपने वायदों को प० बंगाल में 'आपरेशन बरगा' के तहत पूरा भी किया। किंतु १९७८-७९ में संपन्न किसानों, सामंतों और यथास्थितवादियों के घोर समर्थक और नेता चौ० चरण सिंह को जिस प्रकार बिना शर्त समर्थन देकर गद्दीनशीन करने में अपनी अहम भूमिका निभायी, वह भी उनके इस नारे के खोखलेपन को सिद्ध करता है। अपने जिस चौथे मुद्दे पर भी कम्युनिस्ट, दासमुंशी के अनुसार खरे नहीं उतरे हैं, वह है हर प्रकार के विदेशी आक्रमण और आधिपत्य का प्रतिरोध। उनके अनुसार कम्युनिस्टों ने १९६२ में हुए चीनी हमले पर कभी भी सार्वजनिक रुख नहीं लिया। इस 'देशद्रोहिता' के तहत ही एक नयी पार्टी-माकपा का जन्म भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। आज भी माकपा के पोलितब्यूरो ने अपने इस रवैये पर अफ़सोस नहीं जाहिर किया। १९६५ के पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान भी उनका रवैया ठंडा रहा। इतना ही नहीं, बंगलादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई का उन्होंने लगभग खुला विरोध किया और उन्हीं दिनों हुई भारत-सोवियत संधि की पूर्ण उपेक्षा भी की। इसी प्रकार कम्पूचिया पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में भी वह लगातार टालमटोल करते रहे।

दासमुंशी के आरोप कुछ हद तक सही हैं, यद्यपि इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं कि कम्युनिस्टों ने बारंबार नीति-परिवर्तन और समझौते किये हैं—जैसे सत्तारूढ़ होने के पश्चात ज्योति बसु ने निश्चित रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निमंत्रण और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है, किंतु इन्हें केवल मौकापरस्ती और सत्ता बनाये रखने की उनकी चाल मात्र नहीं माना जा सकता। स्वयं ज्योति बसु के शब्दों में यह सैद्धांतिक समझौता उन्होंने 'राज्य को औद्योगिक मरुस्थल न बनने देने के लिए किया क्योंकि केन्द्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी।'

क्या नीति-परिवर्तन अपने में सचमुच एक बड़ा दोष है? इस पर बातचीत करते हुए देश के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता ने अपना नाम न देने के अनुरोध सहित 'माया' से कहा, "प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, जिनके लिए समय-समय पर रणनीति में परिवर्तन करना पड़ता है। किसी भी राजनीतिक दल से यह अपेक्षा करना कि उसकी रणनीति में परिवर्तन नहीं आयेंगे, अनुचित है, क्योंकि राजनीति में असंभव संभव हो जाता है। राजनीति में न स्थायी हित होते हैं—न

सन् ७० से ७७ तक माकपा को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ शंकर राय की अगुवाई में कांग्रेस ने प० बंगाल में कहर बरपाया, जिसमें नक्सलवादियों का लगभग सफाया हो गया। इमरजेंसी में कठिनाइयों की पराकाष्ठा में भी माकपा को कांग्रेस और श्रीमती गांधी के समर्थन का लोभ नहीं सताया। फलस्वरूप १९७७ में जेपी के कंधे पर सवार होकर जनता लहर में पार्टी ने अपने दो प्रमुख गढ़ों—प० बंगाल और त्रिपुरा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। तब से लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में माकपा लगी हुई है।

OF INDIA
CHANDIGARH
SFI-DYFI

केवल रस्मी क्रांति: वामपंथी छात्रों का प्रदर्शन

स्थायी मित्र होते हैं और न स्थायी शत्रु।" राजनीतिशास्त्र के प्रख्यात विशेषज्ञ भवानी सेनगुप्त के अनुसार, "राजनीति का नाम ही प्रवाह और परिवर्तन है। हां, यह आवश्यक है कि यह किसी बड़े हित को ध्यान में रखकर किया गया हो, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लालच के लिए नहीं। अत: यदि इस अवसरवाद का अर्थ केवल सुविधा जुटाना है, तो सही नहीं, क्योंकि पार्टी अभी भी आदर्शवादी है। अवसरों का उपयोग करना दूसरी बात है।"

आरोपों की वजह: प्रश्न यह उठता है कि कम्युनिस्टों पर ढुलमुल और मौकापरस्ती के आरोप लादे क्यों गये? इसका पुराना और सर्वप्रथम कारण एक ओर तो भाकपा का श्रीमती गांधी को दिया खुला और पूर्ण समर्थन, फिर आपातकाल के दौरान उनकी बिगड़ती छवि के कारण किनाराकशी कर लेना रहा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ होने की कामना के मारे माकपा का पहले असंतुष्ट कांग्रेसी अजय मुखर्जी के साथ प० बंगाल में गठजोड़ कर बनी साझा सरकार का मुख्यमंत्री बनाना, बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना रहा है।

प्रश्न यह उठता है कि कम्युनिस्टों पर ढुलमुल और मौकापरस्ती के आरोप लादे क्यों गये? इसका पुराना और सर्वप्रथम कारण एक ओर तो भाकपा का श्रीमती गांधी को दिया खुला और पूर्ण समर्थन, फिर आपातकाल के दौरान उनकी बिगड़ती छवि के कारण किनाराकशी कर लेना रहा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ होने की कामना के मारे माकपा का पहले असंतुष्ट कांग्रेसी अजय मुखर्जी के साथ प० बंगाल में गठजोड़ से बनी साझा सरकार का मुख्यमंत्री बनाना, बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना रहा है।

आरोपों की बढ़ती आंधी का सीधा संबंध कम्युनिस्टों की वर्तमान सुदृढ़ और महत्वपूर्ण स्थिति और अपनाये गये रवैये से है। कम्युनिस्टों ने सभी नयी मुद्राएं अपने को सौदेबाजी की स्थिति में रखने के लिए अपनायी हैं, इससे भवानी सेनगुप्त भी पूर्णतया सहमत हैं। जैसाकि आडवाणी कहते हैं, "हाल की सफलता ने कम्युनिस्टों की महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ा दिया है और आज उनकी दृष्टि केन्द्र की सत्ता पर आ टिकी है। उनकी वर्तमान नीति भी इसी बात की द्योतक है।"

आडवाणी के अनुसार छठे दशक के अंत में जब कम्युनिस्टों ने श्रीमती गांधी का पल्ला पकड़ा था, तो उसके पीछे रणनीति यही थी कि पिछले दरवाजे से सत्ता में शायद प्रवेश मिल जाये। इमरजेंसी के कारण कांग्रेस और श्रीमती गांधी का पतन तथा घोर कम्युनिस्ट विरोधी संजय गांधी के अभ्युदय ने उनके सपनों का महल ढहा दिया था। माकपा को भी अभी तक सीमित सत्ता और क्षेत्र पर ही संतोष करना पड़ा था। किंतु आज संकट में घिरे राजीव गांधी ने इन स्वप्नों को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया है। सरकार और विपक्ष के मध्य स्थित कम्युनिस्ट गुट मौके का पूरा लाभ उठाने की ताक में इस तरह पैंतरे बदल रहा है कि दोनों जहां एक ओर उन्हें अपने साथ लेने के इच्छुक हैं, तो वहीं उनके इस दोतरफा खेल को समझने में असमर्थ। यही नहीं, विपक्ष के बीच भी दीवार खड़ी करने में कम्युनिस्ट काफी हद तक सफल रहे हैं।

कम्युनिस्टों का यह स्वरूप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान खुलकर सामने आया। इससे पूर्व ही केरल, प० बंगाल और त्रिपुरा चुनावों में आशातीत सफलता प्राप्त करने के उपरांत उपजे नये आत्मविश्वास के कारण प० बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने जनता की इच्छाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने वाले विपक्षी विकल्प का आह्वान किया था। इसके तहत ही २५ अप्रैल को सातों गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलायी गयी थी।

जिसमें चर्चा का मुख्य विषय था विपक्षी एकता। किंतु बैठक होने के पूर्व ही माकपा पैंतरा बदल चुकी थी। पार्टी की केन्द्रीय समिति ने बसु के कारगर विपक्षी एकता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बसु ने स्वयं घोषित किया कि यद्यपि विपक्षी एकता के लिए समय अनुकूल है, किंतु फिलहाल "क्या राजीव गांधी का कोई विकल्प है। मुझे तो ज्ञान नहीं," उनका कहना था। इसके बाद ही दोनों पार्टियों की समितियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए विपक्षी दलों से गठजोड़ नहीं करेंगी। इसी दौरान राष्ट्रपति चुनाव की नामजदगी पर उनका अड़ना विपक्षी फूट का शुभारंभ था, किंतु कम्युनिस्ट अपने लक्ष्य मे कामयाब रहे थे। वे भाजपा को राष्ट्रपति चुनाव से अलग हो जाने के लिए विवश कर चुके थे। विपक्षी एकता के अभाव में विपक्ष का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना मात्र प्रतीकात्मक रह गया था। राजीव गांधी पर घिरे संकट के बादल कम्युनिस्टों के इस अप्रत्यक्ष सहयोग के कारण अनायास ही छंट गये। इससे विपक्षी खेमों में क्षोभ और रोष स्वाभाविक था। राजीव सरकार को घेरने का सुनहरा अवसर इनके हाथ से निकल गया था।

बाहर से प्रेरणा का आरोप: विपक्ष के संबंध में कम्युनिस्टों के इस नीति-परिवर्तन के पीछे गत अप्रैल में हुई दो घटनाओं का विशेष हाथ रहा। पहली, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों को राजीव-विरोधी अभियान कम करने की 'सलाह'। कहा जाता है कि दिल्ली स्थित रूसी राजदूत ने स्वयं कलकत्ता जाकर ज्योति बसु को संदेश दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसके द्वारा कांग्रेस के वामपंथी झुकाव वाले गुट ने 'साम्राज्यवादियों से देश बचाओ' की अपील जारी की थी। ठीक यही हथकंडा श्रीमती गांधी सफलतापूर्वक पहले अपना चुकी थीं। इस बार भी कांग्रेसी योजना कामयाब रही।

कम्युनिस्ट दोमुंहे हैं: गुरुपद स्वामी

वामपंथी मौकापरस्त हैं: आडवाणी

सभी वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता इस मत से इनकार करते हैं। भाकपा की राष्ट्रीय परिषद के सचिव एम० फारूकी के अनुसार; "यद्यपि हम सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, फिर भी भारतीय स्थिति पर हमारे विचारों में मतभेद है।" माकपा के वयोवृद्ध नेता बी०टी० रणदिवे भी जोर देकर यही कहते हैं, "भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों पर यह आरोप कि वे विदेशी पार्टियों से आदेश लेती हैं, एकदम मनगढ़ंत है।" भाकपा के महासचिव राजेश्वरराव तब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, जब वह यह घोषणा करते हैं कि "रूसी पार्टी और नेतृत्व अन्य पार्टियों को कभी भी राष्ट्रीय मामलों में सलाह नहीं देते।"

कम्युनिस्टों पर बाहरी प्रभाव का आरोप पुराना है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो स्वयं रूस के काफी करीब थे, इसका मजाक उड़ाते हुए एक बार कहा था "जब मास्को में बारिश होती है, तो छाते दिल्ली में खुल जाते हैं।" फिर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि कठिनाइयों से घिरी कांग्रेस की मदद के लिए रूस ने कई बार हाथ बढाया है, किंतु इसे औपचारिकता प्रदान करने से वह हमेशा कतराया है। उसने संबंध सरकार से बनाये हैं, कांग्रेस पार्टी से नहीं। इसी के तहत वरिष्ठ रूसी नेता डाबरिन की हाल की भारत यात्रा के दौरान जब कांग्रेस ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ औपचारिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की, तो डाबरिन बड़ी कुशलता से बात टाल गये।

इसके कारण न आश्चर्यजनक हैं, न अप्रत्याशित। विधिवत संबंध के पश्चात रूस हमेशा मदद करने के लिए बाध्य रहेगा और सौदेबाजी का रुख अपनाने में सर्वथा असमर्थ। अनौपचारिक संबंधों के बरकरार रहने पर कांग्रेस को हर बार सहायता के लिए रूस के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इससे रूस को जोड़-तोड़ करने में सुविधा रहेगी। इसीलिए रूस 'अभी बस इतनी दूर—और नहीं' की जानी-मानी नीति अपनाता रहा है।

कांग्रेस-कम्युनिस्ट संबंधों ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे है। दोनों का प्रमुख उद्देश्य एक-दूसरे के सहारे अपनी स्थिति मजबूत करना रहा है। एक जाने-माने कांग्रेसी सांसद के अनुसार, "कम्युनिस्ट उस लता के समान हैं, जिन्हें फैलने-फूलने के लिए एक मजबूत दीवार के सहारे की जरूरत होती है। कांग्रेस में उन्हें सही दीवार नजर आयी, जिसके सहारे उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तृत करने का प्रयास समय-समय पर किया है।" कांग्रेस ने भी जब-जब अपनी नैया को भंवर में फंसते पाया है, तब-तब कम्युनिस्टों को पतवार बनाया है। मतलब निकलने या न निकलने पर दोनों दलों ने एक-दूसरे से पल्लू झाड़ लेने में न देर की है, न संकोच।

इसकी मिसाल अभी हाल में भी देखने को मिली है। जिन कम्युनिस्टों ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 'राजीव बचाओ' का काम परोक्ष सहयोग द्वारा पूरा किया था, वही तुरंत बाद मध्यावधि चुनाव का नारा बुलद कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने 'माया' से इस पैंतरेबाजी का खुलासा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो उनकी भूमिका रही थी, उसका औचित्य वह किसी भी प्रकार समझाने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। दूसरे राजीव-विरोधी आंधी में वह पूरी तरह अलग-थलग पड़ गये थे।"

विपक्ष के साथ खेल दूसरे ही रहे हैं। कांग्रेस से नाराज या त्रस्त कम्युनिस्ट दलों ने कई बार विपक्ष के साथ सरकार गिराने, कांग्रेस का विकल्प तैयार करने के मंसूबे बांधे हैं। इमरजेंसी के बाद १९७७ के चुनाव में उन्होंनें इसे पूरा होते भी देखा है। किंतु उसके बाद प्राय: अंतिम कदम उठाने से पहले वे या तो रुक गये हैं या उन्होनें मार्ग बदल लिया है। एक तो जनता सरकार का कटु अनुभव उन्हें रुकने को बाध्य करता रहा है, दूसरे वर्तमान विपक्ष को कांग्रेस का विकल्प हो जाने में उन्हें कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं दिया है। जैसा कि इन्द्रजीत गुप्त स्वीकारते हैं, "सत्ता कांग्रेस के पास रहे या जनता पार्टी अथवा लोकदल या भाजपा के पास कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बुर्जुआ पार्टी हैं जो जनता के हितों की उचित

रक्षा नहीं कर सकतीं।" सत्य तो यह है कि कम्युनिस्ट कांग्रेस के विकल्प के रूप में केवल अपने को देखने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, किंतु दूरदर्शी और विचारशील हैं, इसलिए यह भी समझते हैं कि समय परिपक्व नहीं है। इसीलिए फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने में हानि नहीं समझते। खासकर इस समय जब उनकी अपनी भूमिका सरकार और विपक्ष दोनों के बीच महत्वपूर्ण हो गयी है।

अनेक विपक्षी नेताओं का मत है कि आज कम्युनिस्ट विपक्ष के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के समांतर सांप्रदायिकता-विरोधी अपने नारे से आंदोलन को निष्प्रभावी करने में लगे हैं। उनकी यह पैंतरेबाजी सूरजकुंड में देवीलाल द्वारा आयोजित विपक्षी दलों के सम्मेलन में भी देखने को मिली, जहां उन्होंने भाजपा की मौजूदगी के कारण उसका बहिष्कार किया। किंतु बाद में एन०टी० रामाराव के चुनाव में सुधार के लिएं आयोजित बैठक में भाजपा की मौजूदगी के बावजूद शिरकत की।

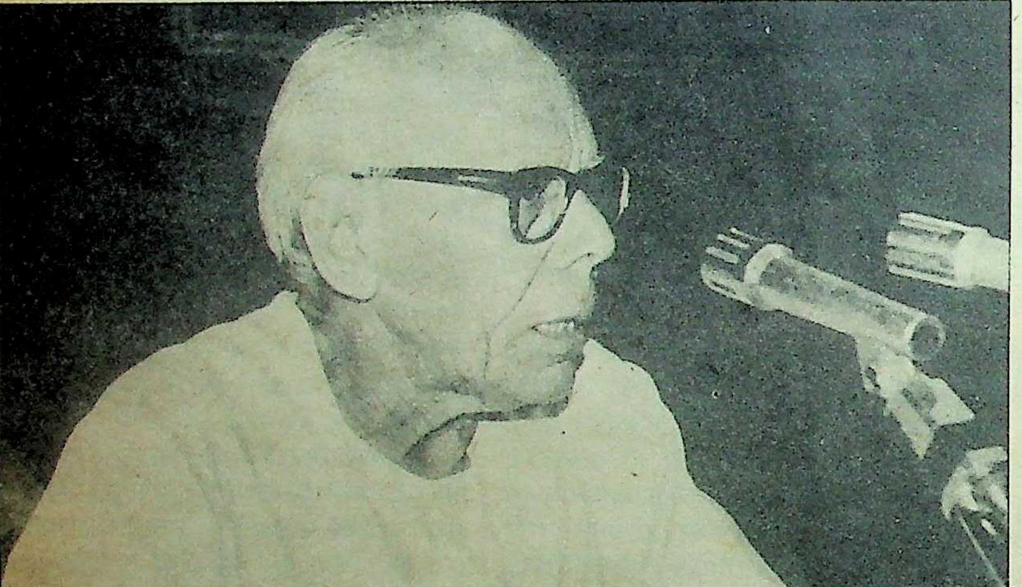

रूस हमारा केवल दोस्त है: एम० फारूकी

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कम्युनिस्ट उनके बीच हुए मनमुटाव व विभाजन के लिए नारद मुनि की भूमिका निभाने में सफल रहे हैं। कम्युनिस्टी चाल की दूरंदेशी ने विपक्ष में जो उथल-पुथल मचायी है, उससे संगठित विपक्ष तो दुःस्वप्न के समान हो गया है और भाजपा पूर्णतः अलग-थलग पड़ गयी है। स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनकी उज्ज्वल छवि और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये लोकप्रिय अभियान का सहारा लेकर विपक्ष राजीव सरकार को खुली चुनौती देने की चेष्टा कर रहा था, की स्थिति अजीबोगरीब हो गयी है। कम्युनिस्टों के जाल में विपक्षी कुछ ऐसे उलझ गये हैं कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें दोनों—कम्युनिस्ट और भाजपा—में से एक का हाथ थामना और एक का छोड़ना पड़ सकता है।

भाजपा और कम्युनिस्टों के मध्य छिड़ी लड़ाई का मूल मुद्दा यही है कि किसी भी प्रकार सिंह को अपने साथ ले लिया जाये। दोनों दलों में अनेक समानताएं हैं। दोनों कार्यकर्ता आधारित, अनुशासित दल हैं। दोनों के प्रभाव क्षेत्र सीमित हैं। दोनों ही इसे विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील हैं विशेषकर हिंदीभाषी क्षेत्रों में। और इस काम में विश्वनाथ प्रताप सिंह से अधिक अच्छा सहारा उनका कौन हो सकता है? किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह की गति सांप-छछूंदर जैसी हो गयी है। यद्यपि अभी तक अपनायी सभी नीतियां उन्हें भाजपा के समीप ही ले जाती हैं, किंतु समय की अनिवार्यताएं कुछ ऐसी हैं जो उन्हें कम्युनिस्टों को अपना 'स्वाभाविक सहयोगी' घोषित करने के लिए बाध्य करती हैं। विपक्ष के एक अनुभवी नेता ने इस विषय पर बातचीत करते हुए 'माया' को बताया, "विश्वनाथ प्रताप सिंह तीन-तीन परेशानियों के शिकार हो गये हैं। एक, फेयरफैक्स में उनकी भूमिका। उन पर सीआईए का एजेंट होने की तोहमत लग सकती है—कम से कम सरकार ऐसा प्रयास अवश्य करेगी। दूसरा, उनके सिर पर राजा का खिताब भी है जो उन्हें जनता से दूर कर सकता है। तीसरे, वित्तमंत्री के रूप में जो पूंजीवादी आर्थिक नीतियां अपनायी थीं, वे आज उनके विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती हैं। कम्युनिस्टों का पल्ला पकड़ने से उन्हें इन तीनों से बच निकलने का मौका मिलेगा, ऐसी उनकी धारणा हो गयी है। यही उन्हें कम्युनिस्टों का हाथ थामने को विवश कर रही है।" किंतु भाजपा अध्यक्ष आडवाणी की चिन्ता का कारण कुछ और है। उनका मानना है कि आपस में फूट डलवाकर कम्युनिस्ट विपक्ष को तो कमजोर कर ही रहे हैं, स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी धोखा देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी को, काम निकल जाने पर, दिया था।

धोखाधड़ी, मौकापरस्ती, पैंतरेबाजी आदि आरोपों का जोरदार खण्डन करते हुए इन्द्रजीत गुप्त ने 'माया' से कहा, "सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। अधिकतर आरोप इसलिए लगाये जाते हैं कि हम कुछ मुद्दों का समर्थन करते हैं और कुछ का विरोध। यह सरकार और विपक्ष दोनों पर बराबर लागू होता है। जैसे हमने सरकार की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का हमेशा समर्थन किया है। मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की नीति को सराहा है, धर्मनिरपेक्षता की नीति की वकालत की है, किंतु उसकी आर्थिक, भूमि संबंधी नीतियों का कट्टर विरोध किया है। यह न ढुलमुलपन की निशानी है, न पैंतरेबाजी। हम मुद्दों को स्वीकारते-नकारते हैं, उनकी अपनी अच्छाइयों-बुराइयों पर सोचने, समझने, परखने के बाद। न अंध समर्थन करते हैं न अंध विरोध।" यही रवैया उन्होंने विपक्ष के साथ भी अपनाया है। वह प्रत्येक विपक्षी मुद्दे को उसके गुणावगुण के तहत ही तौल रहे हैं। गुप्त ने बताया कि विकल्प की तलाश उन्हें भी है किंतु 'जनता' राज्य का अनुभव इतना कटु रहा है कि आज फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाने को वह विवश हैं, "हम मूलगामी परिवर्तन चाहते हैं। विकल्प के लिए हमें पुराना जोड़तोड़ स्वीकार नहीं। विपक्ष कोई ठोस कार्यक्रम क्यों नहीं हमारे सम्मुख रखता? सभी विपक्षी दलों के नेता समान कार्यक्रम की बात से कतरा रहे हैं। कुछ समय पहले कलकत्ता में हुई गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान एक ठोस कार्यक्रम बनाया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि आज उसे कोई विपक्षी नेता देखना भी पसन्द नहीं करता है। उनका कार्यक्रमविहीन कोई सरकार गिराओ आन्दोलन हम कैसे स्वीकार कर सकतें हैं?"

भाजपा से लड़ाई: भाजपा से छिड़ी लड़ाई पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वह हमेशा

"यद्यपि हम सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, फिर भी भारतीय स्थिति पर हमारे विचारों में मतभेद है।"

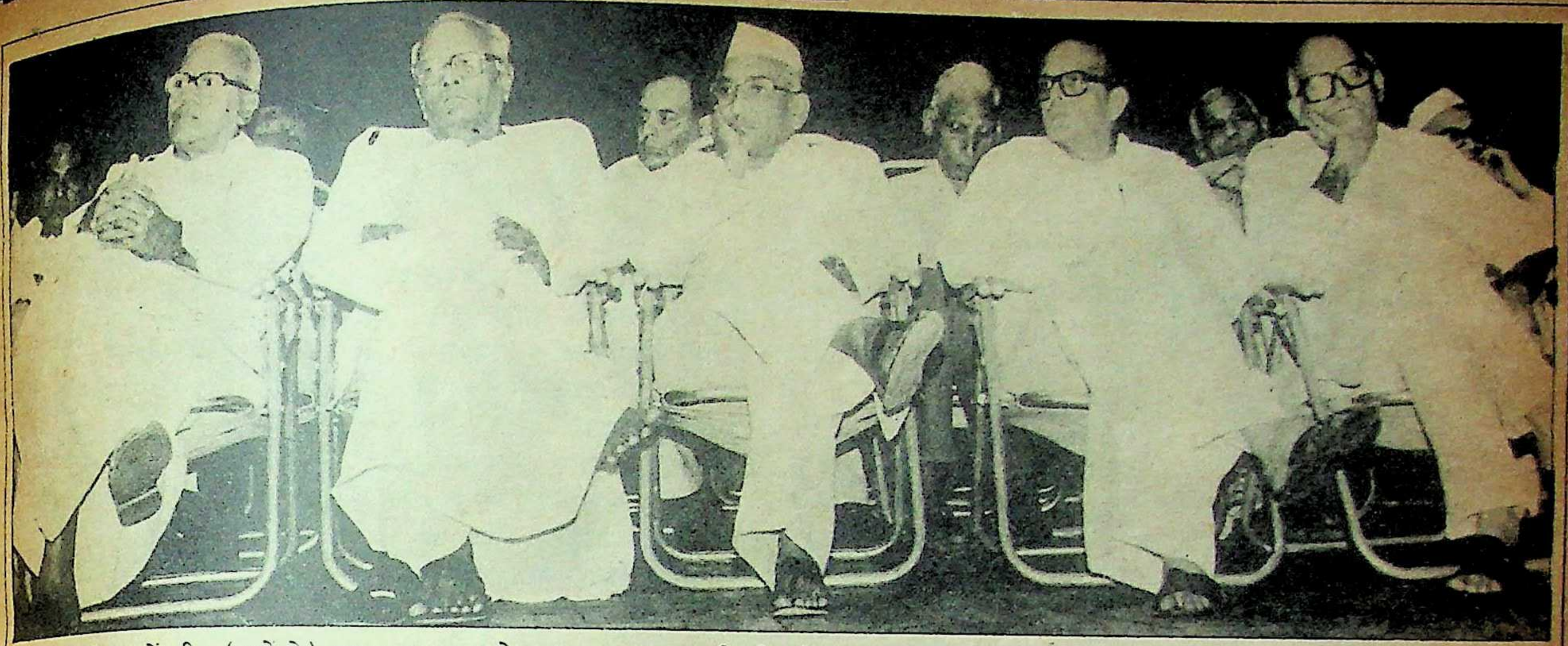

पक्ष में भी, विपक्ष में भी : (बायें से) कृष्णा अय्यर, राजेश्वर राव, बहुगुणा, वी०पी० सिंह, चंद्रकांत यादव

साम्प्रदायिकता विरोधी रहे हैं। "सूरजकुंड अधिवेशन में हमने इसलिए भाग नहीं लिया, क्योंकि वहां कुछ होना ही नहीं था। न कोई कार्यक्रम था, न कोई मुद्दा। रामाराव द्वारा बुलायी गयी बैठक चुनाव-सुधार के विशिष्ट मुद्दे पर थी। इसीलिए भाजपा की मौजूदगी के बावजूद हमने उसमें भाग लिया और क्या भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का एकाधिकार है और अन्य सभी दल दूध के धुले हैं ?"

चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय—साथियों, सहयोगियों का चुनाव कम्युनिस्टों के लिए हमेशा दुविधा का विषय रहा है। भवानी सेनगुप्त के अनुसार, "सहयोगियों के चयन में कम्युनिस्टों ने बार-बार गलती की है। उनकी महानता यही है कि गलती स्वीकारने-सुधारने में वे कभी भी हिचकिचाये नहीं हैं।"

कम्युनिस्टों को करीब से जानने वाले एक विपक्षी नेता ने उनकी कार्यप्रणाली और शक्ति की चर्चा के दौरान बताया, "वे देर आये पर दुरुस्त आये में विश्वास रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है—आत्मालोचन और विचार-विमर्श। भारी से भारी गलती को वे सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हैं। उनकी कांग्रेस सात दिन तक चलती है। दल के भीतर विचार-विमर्श एक साल पहले ही शुरू हो जाता है। शेष राजनीतिक दलों के वार्षिक अधिवेशन मात्र 'जम्बोरी' होते हैं। कम्युनिस्टों के अधिवेशनों में होता है हृदय मंथन-विचार मंथन। अर्धविराम, पूर्णविराम तक पर बहस होती है। फिर इसके बाद हुए सामूहिक निर्णय पर पूर्ण निष्ठा होती है। मनसा, वाचा, कर्मणा उसका पालन किया जाता है। इसके विपरीत अन्य दलों में आन्तरिक द्वन्द्व चलता रहता है।"

कम्युनिस्टों की यह कार्यप्रणाली और पढ़े-लिखे नौजवान, एकनिष्ठ, समर्पित, अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता उनकी विशेष पूंजी हैं। इसीलिए सीमित जनाधार के बावजूद देश के राजनीतिक-रंगमंच पर उनकी भूमिका दिनो-दिन सुदृढ़ और निर्णायक बनती जा रही है। कमजोर होती कांग्रेस इनके लिए वरदान सिद्ध हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के बाद सर्वाधिक आर्कषक और जनप्रिय कार्यक्रम-भले ही वे केवल नारे ही क्यों न हों- इन्हीं के पास हैं। अपने बढ़ते महत्व का ज्ञान कम्युनिस्टों को उतना ही है, जितना कांग्रेस या विपक्ष को। यही कारण है कि उनके प्रत्येक कार्य और कदम को आज विशेष रूप से जांचा-परखा जा रहा है।

जान बूझकर अपनायी गयी अस्पष्ट स्थिति को यदि विपक्ष कम्युनिस्टों की दुरंगी चाल घोषित कर रहा है, तो कांग्रेस के दासमुंशी इसे सत्तारूढ़ होने की तिकड़म बताते हैं। उनके अनुसार, "कम्युनिस्टों का मुख्य ध्येय केन्द्र में साझा सरकार बनाकर पहले सत्तारूढ़ होना है, बाद में धीरे-धीरे अपने पांव फैलाकर ब्लैकमेल कर प्रभुत्वपूर्ण स्थान हासिल करना है। स्थिति स्पष्ट न करने में वे इतने ज्यादा माहिर हैं कि नाव पर सवार होने के बाद भी वे यह नहीं बतलायेंगे कि किस दिशा में जायेंगे—केवल नदी और तट की सुंदरता का बखान करेंगे।"

दासमुंशी की आलोचना पक्षपात पूर्ण हो सकती है, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल व केरल में थोड़ी बहुत खींचतान के बावजूद सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो वह दस वर्षों से अधिक मोर्चा सरकार चलाने में कामयाब हुए हैं किन्तु इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं कि अस्पष्टता की यह मुद्रा कम्युनिस्टों ने जान बूझकर अपनायी है, स्थिति की नाजुकता को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए जैसाकि भाजपा सहित सभी मानते हैं कि जहां तक कम्युनिस्टों के जनाधार और प्रभाव के अंकगणित का प्रश्न है, उसमें तालमेल नहीं है। अपनी इस मजबूत स्थिति को उसकी तार्किक परिणति पर ले जाने की महत्वाकांक्षा भी उनमें दिनो-दिन बढ़ रही है। जैसाकि भवानी सेनगुप्त कहते हैं, "कम्युनिस्ट आज अपनी सौदेबाजी की स्थिति खोना नहीं चाहते। वे सभी दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव कल नहीं होने वाले हैं। इस बीच कितने संबंध बनेंगे-बिगड़ेंगे, कौन कह सकता है ? यदि वे बाद में भाजपा से भी कोई समझौता कर लें, तो मुझे आश्चर्य न होगा।" कम्युनिस्टों का यही बदलता स्वरूप और चौराहे पर खड़े रहना एक अन्य राजनीतिक पर्यवेक्षक के अनुसार पार्टी के वर्ग चरित्र को तो समाप्त कर ही चुका है। बुर्जुआ पार्टियों से बढ़ते मेलजोल के कारण वे अपने नाम से कम्युनिस्ट शब्द भी कितने दिनों तक अपनाये रखेंगे, कहा नहीं जा सकता। सत्तारूढ़ होने के पश्चात उनका मूल चरित्र बना रहेगा, इसमें संदेह है।" लगभग ऐसा ही संदेह जनता पार्टी के प्रमुख नेता गुरुपदस्वामी भी व्यक्त करते हैं, मगर एक सर्वथा नये कोण से, "कम्युनिस्ट यदि केन्द्र में सत्तारूढ़ हुए, तो क्या वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रख विपक्ष को फलने-फूलने का अवसर देंगे अथवा तानाशाही कायम कर भारतीय राजनीति को एक अंधी गली में पहुंचा देंगे ?"

—रंजना [illegible]

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कम्युनिस्ट उनके बीच हुए मनमुटाव व विभाजनके लिए नारद मुनि की भूमिका निभाने में सफल रहे हैं। कम्युनिस्टी चाल की दूरंदेशी ने विपक्ष में जो उथल-पुथल मचायी है, उससे संगठित विपक्ष तो दुःस्वप्न के समान हो गया है और भाजपा पूर्णतः अलग-थलग पड़ गयी है।

तथ्य-कथ्य

रिलायंस कप में बने रिकार्ड

१. **भारत** के मध्यम तेज गेंदबाज चेतन शर्मा विश्वकप प्रतियोगिताओं में 'हैट्रिक' बनाने वाले पहले गेंदबाज बन गये हैं। उन्होंने रिलायंस कप के अंतिम लीग मैच में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन गेंदों में रदरफोर्ड (२६), स्मिथ (०) और चेटफील्ड (०) को पवेलियन वापस भेज दिया।

एक दिवसीय क्रिकेट में चेतन के अलावा दो और गेंदबाजों ने हैट्रिक बनायी है। पाकिस्तान के जलालुद्दीन ने १९८२-८३ में हैदराबाद (पाक०) में आस्ट्रेलिया खिलाफ और आस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रूस रीड ने १९८५-८६ में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनायी थी।

२. **कराची** में श्रीलंका के खिलाफ १८१ रन बनाकर वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने भारत के कपिल देव के १७५ रन का विश्वकप कीर्तिमान तोड़ दिया। कपिल देव ने यह रिकार्ड जिबाब्वे के खिलाफ पिछले विश्वकप में टर्नब्रिज वेल्स में बनाया था। रिचर्ड्स ने अपने १८१ रन सोलह चौकों और छह छक्कों की मदद से बनाये, जबकि कपिल देव ने नाबाद रहते हुए सत्रह चौके और छह छक्के लगाकर १७५ रन जोड़े थे।

कप्तान के रूप में असफल, परतु व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहा: **रिचर्ड्स**

एक दिवसीय मैचों में भी ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान रिचर्ड्स के नाम है। १९८४ में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मानचेस्टर में नाबाद १८९ रन बनाये थे।

३. **करांची** में ही वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ विश्वकप का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज ने पचास ओवर में सात रन प्रति ओवर से भी ज्यादा गति से चार विकेट पर ३६० रन बनाये। इसके पहले स्वॉसी में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा साठ ओवर में बनाये गये पाच विकेट पर ३३८ रन सर्वाधिक टीम स्कोर था।

एक दिवसीय मैचों के हिसाब से भी पचास ओवर में बनाया गया यह सर्वाधिक स्कोर है। इसके पहले आस्ट्रेलिया ने एडिलेड में श्रीलंका के खिलाफ १९८४-८५ में दो विकेट पर ३२३ रन बनाये थे।

४. **उक्त** शतक के साथ ही रिचर्ड्स एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा दस शतक बनानेवाले बल्लेबाज हो गये। डेस्मंड हेंस ने इसी मैच में १०५ रन बनाकर अपना नवां शतक बनाया।

५. **विश्वकप** में सबसे ज्यादा करीबी हार भारत को झेलनी पड़ी। रिलायंस कप में अपने पहले ही मैच में उसे आस्ट्रेलिया से मद्रास में एक रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले १९७९ में ओल्ड ट्रेफर्ड (मानचेस्टर) में न्यूजीलैंड केवल नौ रन से हारी थी, जबकि विकेटों के लिहाज से १९७५ में बर्मिघम में पाक टीम वेस्टइंडीज से मात्र एक विकेट से हारी थी।

एक दिवसीय क्रिकेट में एक रन से पराजय का यह तीसरा मौका था। इससे पहले न्यूजीलैंड ने (१९७६-७७) में पाकिस्तान को सियालकोट में और न्यूजीलैंड ने ही आस्ट्रेलिया को १९८०-८१ में एक रन से हराया था।

६ **न्यूजीलैंड** के खिलाफ गावस्कर द्वारा बनाया गया शतक विश्वकप के इतिहास का दूसरा तेज शतक था। गावस्कर ने ८५ गेंदों में १४९ मिनट में यह शतक बनाया। इसके पहले वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने १९७५ में विश्वकप में केवल ८२ गेंदों में शतक बनाया था। एक दिवसीय मैचों में यह गावस्कर का पहला शतक था। भारत की ओर से विश्वकप में लाने वाला यह दूसरा शतक है।

७. **उक्त** शतक के साथ ही गावस्कर एक दिवसीय मैचों में तीन हजार रन बनानेवाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गये। उन्होंने ये रन १०६ मैचों में बनाये।

८. **रिलायंस** कप में न्यूजीलैंड के ऊपर भारत की जीत सबसे बड़ी जीत थी। उसने न्यूजीलैंड को नौ विकेट से हराया। इसके पहले भारत ने जिबाब्वे को और इंग्लैंड ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी।

९. **पहले** विकेट की साझेदारी में गावस्कर और श्रीकांत द्वारा बनाये गये १३६ रन नया भारतीय रिकार्ड है। इसके पहले १९७५ के विश्वकप में फारुख इंजीनियर और गावस्कर ने पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ लीड्स में पहले विकेट की साझेदारी में १२३ रन बनाये थे।

१०. **चारों** विश्वकप में वेस्टइंडीज पाकिस्तान से पहली बार १६ अक्तूबर को हारी। इसके पहले उसे हराने का श्रेय केवल इंग्लैंड और भारत को था।

११. **आस्ट्रेलिया** के खिलाफ दूसरे मैच में भारत ने छह विकेट पर २८९ रन बनाये, जो विश्वकप में उसका सर्वाधिक स्कोर है। इसके पहले इसी विश्वकप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाये गये २६८ रन सर्वाधिक स्कोर था।

१२. **दो** बार की विश्वकप विजेता और एक बार उपविजेता रहनेवाली वेस्टइंडीज रिलायंस कप में सेमीफाइनल में भी स्थान नहीं बना सकी, जबकि इंग्लैंड अकेली ऐसी टीम है जो चारों विश्वकप में सेमीफाइनल में पहुंची हो।

१३. **फैसलाबाद में** पाकिस्तान के खिलाफ रवि रत्नायके ने विश्वकप में अपना और श्रीलंका की ओर से पहला शतक लगाया।

आस्ट्रेलिया ने पहली दफा विश्वकप जीता **संकलन—मुकेश जैन**

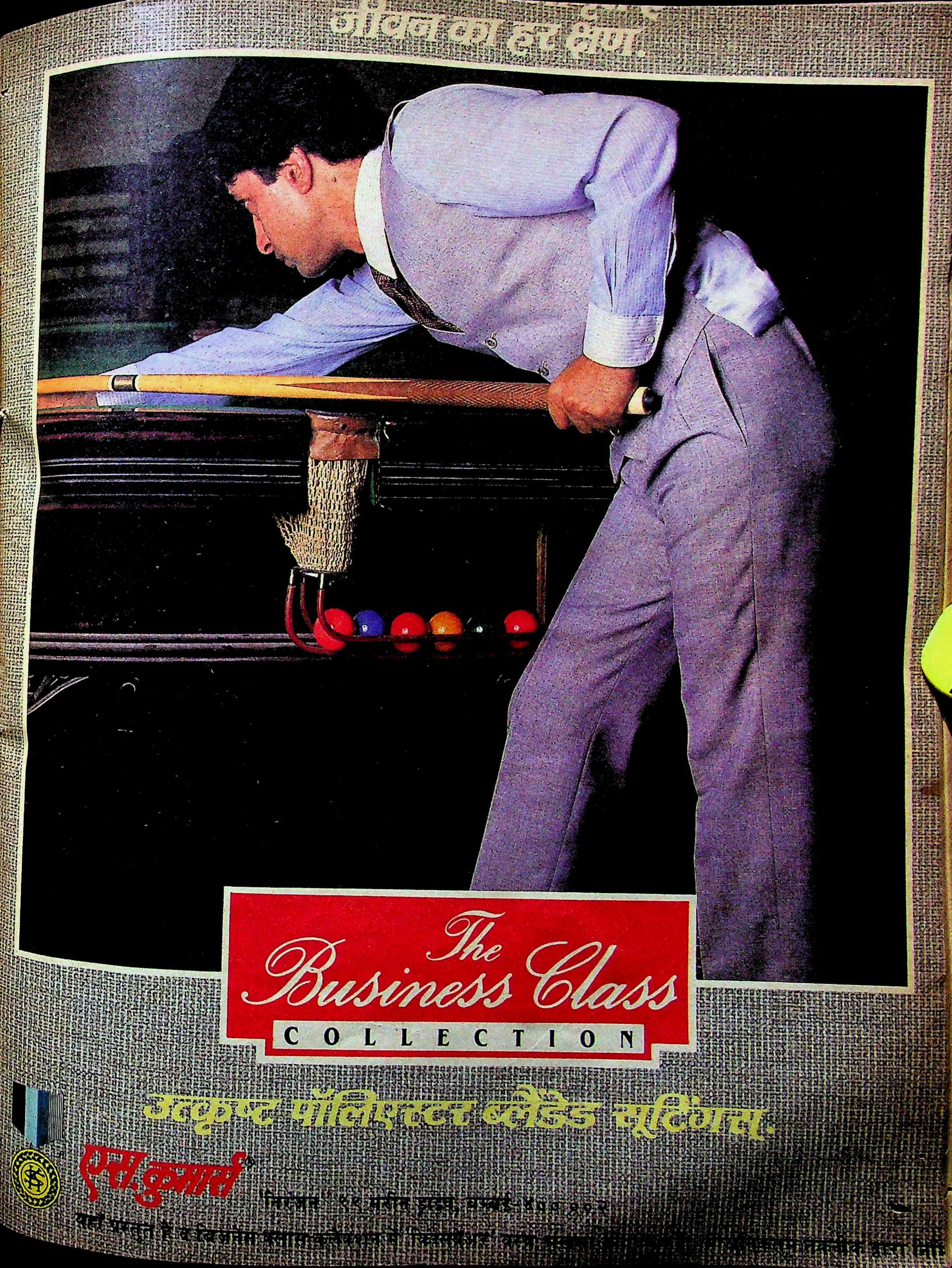
जीवन का हर क्षण.
The Business Class
COLLECTION
उत्कृष्ट पॉलिएस्टर ब्लैंडेड सूटिंग्स.
एस.कुमार्स®
'निरंजन' ९९ मरीन ड्राइव, बम्बई-४०० ००२
यहाँ प्रस्तुत है व बिज़नेस क्लास कलेक्शन में [illegible]

हिन्दू उग्रवाद का शंखनाद

यह आम धारणा रही है कि देश में ८० प्रतिशत आबादी हिन्दुओं की होने के कारण अल्पसंख्यक भयभीत रहते हैं और यही असुरक्षा का भाव उनमें सांप्रदायिकता के बीज बोता है। लेकिन अब हालात ने कुछ ऐसा मोड़ ले लिया है कि बहुसंख्यक हिन्दुओं के मन में यह धारणा घर करने लगी है कि सरकार अल्पसंख्यकों को अपना 'वोट बैंक' मानती है, इसलिए उनकी अनुचित मांगें भी मान लेती है, लेकिन हिन्दुओं की न्यायोचित मांगों की परवाह तक नहीं करती। इस धारणा को और अधिक धार्मिक कट्टरता में उन संगठनों ने बदलना शुरू कर दिया है जो यह प्रचार कर रहे हैं कि हिन्दुओं की पहचान एवं अस्तित्व खतरे में है। इन संगठनों की सक्रियता का ही परिणाम है कि हिन्दुओं में गोलबंद होने की प्रवृत्ति पैदा होने लगी है। यदि इस प्रवृत्ति ने दूसरे धार्मिक समुदायों के प्रति नफरत का रूप ले लिया, तो यह देश और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे घातक बात होगी। बहुसंख्यकों में सांप्रदायिकता को जन्म देनेवाली कौन सी परिस्थितियां हैं? क्या विभिन्न हिन्दू संगठन इस आग को हवा देने में लगे हैं? :

खतरनाक आक्रामकता: हिन्दू पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां

राम जन्म भूमि को लेकर जहर उगलने में लीन शहाबुद्दीन और शंकराचार्य 'यह याद रखने की जरूरत महसूस नहीं करते कि माटुंगा (बंबई) में मस्जिद और मंदिर अगल-बगल हैं तथा दोनों धर्मों के अनुयायी अपने-अपने पूजा स्थल में सद्भाव के साथ धार्मिक कार्य संपन्न करते आ रहे हैं। न ही अलगाववादी सिख यह देख कर शर्म से गड़ते हैं कि उनकी बंदूकों के डर से २२ अक्तूबर को हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में दिवाली के दिये नहीं जले। इस परम पवित्र मंदिर के ३८७ वर्ष के इतिहास में ऐसी अभागी बात पहली दफा हुई है।

राजनीतिक अखाड़ियों और धर्म के इजारेदारों ने नाजुक धार्मिक भावनाओं को इस कदर कुरेदा है कि देश की आबादी में ८० प्रतिशत स्थान रखने वाले हिंदू भी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं— खासकर मध्यमवर्गीय हिंदुओं के मन में तो यह भावना अंकुरित होने लगी है कि 'हिंदू राज्य' के बिना उनकी पहचान का बचना मुश्किल है।

उकसावा: यही कारण है कि विश्वहिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल को हिंदुओं के अस्तित्व की चिंता सता रही है। (देखिए साक्षात्कार) इसी भावना का ही परिणाम है कि मेरठ का 'शिव शक्ति दल' ऐसी मुहीम में लगा है, जिससे हिंदूवादी सांसद और विधायक ही वहां से चुन कर आ सकें। इसी कारण पुरी के शंकराचार्य राजीव गांधी को ललकार रहे हैं कि या तो हिंदुओं की सुरक्षा की सारी मांगें वह मान लें, अन्यथा अनियंत्रित प्रतिशोध की ज्वाला को धधकने से कोई नहीं रोक सकता। (देखिए साक्षात्कार)

> राजनीतिक अखाड़ियों और धर्म के इजारेदारों ने नाजुक धार्मिक भावनाओं को इस कदर कुरेदा है कि देश की आबादी में ८० प्रतिशत स्थान रखनेवाले हिन्दू भी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।

बाल ठाकरे भी हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि वे अल्पसंख्यकों की तरह शस्त्र सज्जित हो जायें। हिंदू मंच के राकेश सोबती याद दिला रहे हैं कि सारे हिंदू देवता आयुधधारी हैं— शिव के पास त्रिशूल है, कृष्ण के पास चक्र है और राम धनुर्धारी हैं, इसलिए हिंदुओं का शस्त्र-धारण करना धर्मानुकूल है।

ऐसे अशुभ संकेत पहली दफा दिखायी पड़ रहे हैं कि हिंदुओं में भय-भावना घर कर रही है। वे अपनी पहचान खतरे में पा रहे हैं और यह सोच कर के क्षुब्ध हैं कि अल्पसंख्यक तो सरकार के दुलारे हैं, लेकिन सरकार को हिंदुओं की कोई परवाह नहीं। हिंदुओं पर ही सबकी मार पड़ती है। बढ़ती सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की यह भावना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कितनी खतरनाक हो सकती है— इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

गत दिनों दिल्ली में संपन्न हुई राज्यपालों की बैठक में राष्ट्रपति आर० वेंकटरमण और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भाषणों में चिंता का मुख्य मुद्दा यही सांप्रदायिकता थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारी तात्कालिक प्राथमिकता सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरपन से जूझना है। जाहिर है देश के सर्वोच्च व्यक्ति भारतीय राजनीति में धार्मिक गोलबंदी के बढ़ते दबाव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन नेताओं ने सत्ता हथियाने के लिए बेहयायी से धार्मिक भावनाओं को भड़काया है, उन्हें खमियाजा न उठाना पड़ा हो। जून १९८४ में जब जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए, तो कांग्रेस-इ के नेताओं ने जम्मू क्षेत्र के मतदाताओं को यह वादा करके ललचाया था कि वे उन्हें शेख अब्दुल्ला परिवार के शिकंजे से निकालेंगे। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मत नहीं मिले। ये मत मिले इंदिरा गांधी को। उनकी पार्टी

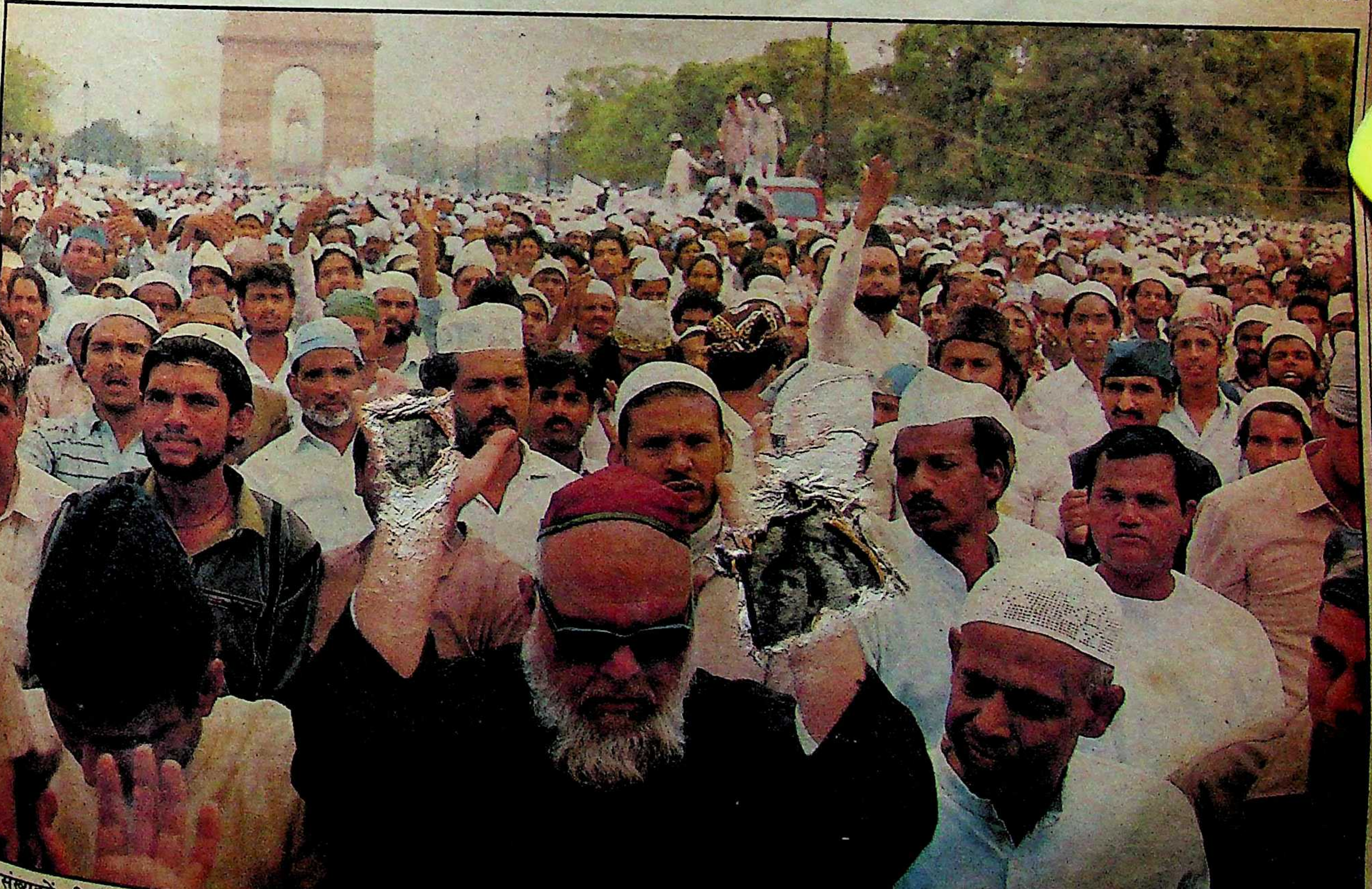

बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता की एक वजह: बोट क्लब पर मुसलमानों की विशाल रैली

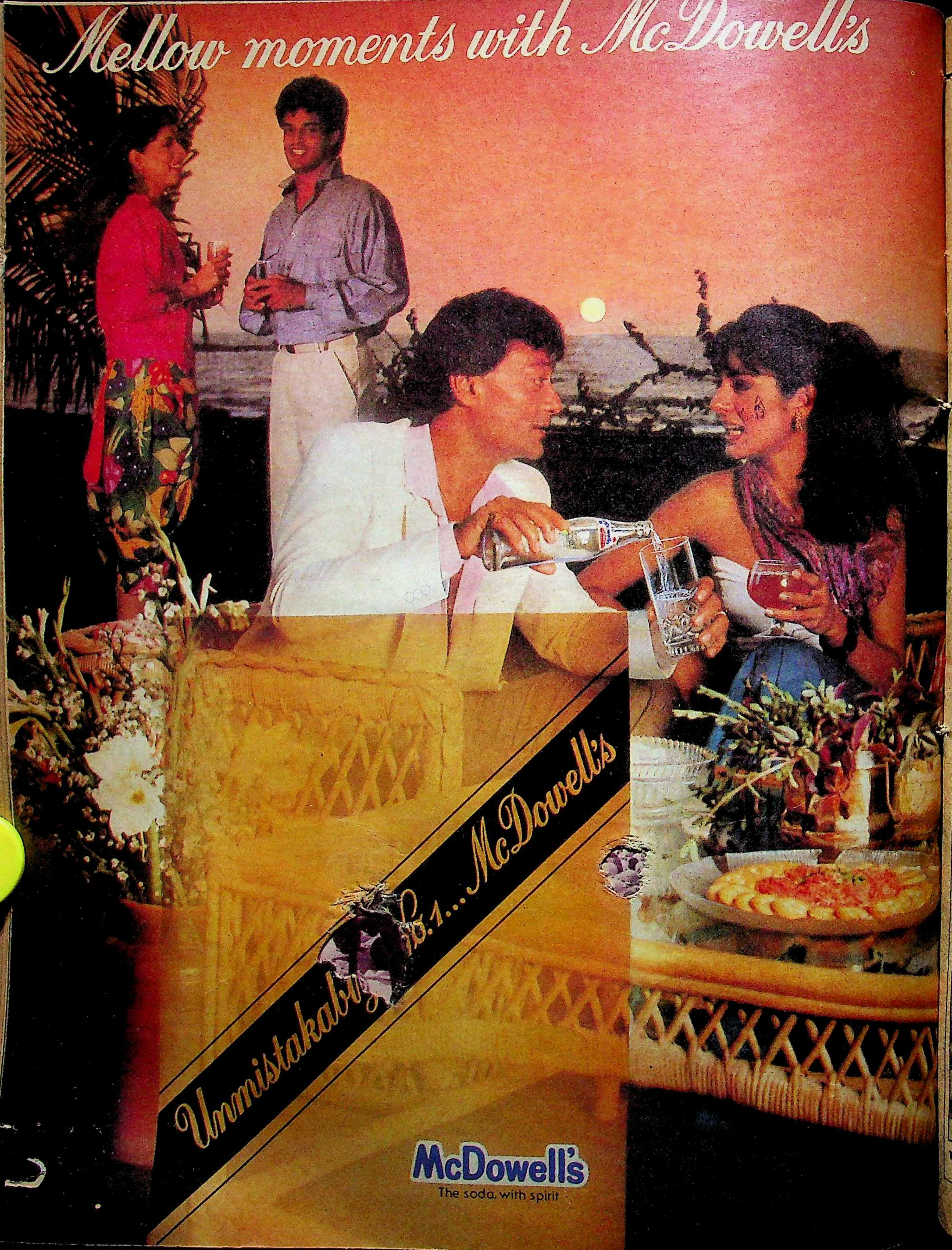
Mellow moments with McDowell's
Unmistakably No.1... McDowell's
McDowell's
The soda, with spirit

१९८२ में श्रीमती गांधी ने ही विश्व हिंदू परिषद के हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था। अब वही विश्व हिंदू परिषद राम जन्म भूमि के लिए आंदोलन कर रही है, जिसके कारण उसकी निंदा की जा रही है। अदालती आदेशों से ही सही, लेकिन लगभग चार दशक बाद जब वही राम जन्म भूमि मंदिर पुरोहितों को सौंपा गया, तो दूरदर्शन पर समाचारों के प्रमुख समय में करीब दो मिनट का समय इस घटना को दिया गया। इसी तरह की शह मुस्लिम कठमुल्लाओं को दी जा रही है।

जीती तो सही, लेकिन राज्य को हिंदू-मुस्लिम दो खेमों में बांट दिया। १९८२ में श्रीमती गांधी ने ही विश्व हिंदू परिषद के हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था। अब वही विश्व हिंदू परिषद राम जन्म भूमि के लिए आंदोलन कर रही है, जिसके कारण उसकी निंदा की जा रही है। अदालती आदेशों से ही सही, लेकिन लगभग चार दशक बाद जब वही राम जन्म भूमि मंदिर पुरोहितों को सौंपा गया, तो दूरदर्शन पर समाचारों के प्रमुख समय में करीब दो मिनट का समय इस घटना को दिया गया। इसी तरह की शह मुस्लिम कठमुल्लाओं को दी जा रही है। प्रतिगामी और पुरातनपंथी तत्वों के दबाव में आकर मुस्लिम विधवा विधेयक पारित करना—इसी का ज्वलंत उदाहरण है। इस मामले में केवल कांग्रेस ही गुनहगार नहीं है, दूसरे दल भी उतने ही दोषी हैं। यों तो जनता पार्टी अपने को कांग्रेस से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है, लेकिन राम जन्म भूमि विवाद को लेकर शहाबुद्दीन जो कट्टरवाद और सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, उस पर वह मौन है। बेपरवाह और बेलगाम शहाबुद्दीन हाल में वैंकुवर में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा गये थे। जिस विषय पर चर्चा हुई, वह था: भारत के अल्पसंख्यकों पर दासता और अस्तित्वहीनता का मंडराता खतरा। जनता पार्टी के एक नेता कल्याण सिंह कालवी जो राजस्थान शाखा के सचिव हैं, सती प्रथा को जारी रखने के लिए झंडा उठाये फिर रहे हैं।

सांप्रदायिकता को नया मोड़: दरअसल धार्मिक मांगों को सांप्रदायिक मोड़ मिलना उस समय से शुरू हुआ है, जब से मीनाक्षीपुरम में व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हुआ और पंजाब में हिंसा का उबाल आया। उस समय चुनाव की पूर्व संध्या पर हिंदू परिषद की ओर से पर्चे बांटे गये, जिनमें से एक में कहा गया था कि 'हिंदू समाज' चुनावों में उन्हीं उम्मीदवारों को मत दें जो यह करार करें कि वे एक ऐसा अधिनियम पास करवायेंगे, जिसमें 'हिंदू समाज को राम जन्म भूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्थानों को वापस दिलाने' की व्यवस्था हो।

दूसरी ओर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी ऐसी हरकतें करते हैं, जिनमें राष्ट्रद्रोह की बू आती है। चाहे वास्तव में उनके मन में देश के प्रति नफरत भले ही न हो, लेकिन लोगों को डराने के लिए ऐसा दिखाने के लिए वे हर समय आतुर रहते हैं। मसलन कश्मीर में जिस भी नेता की लोकप्रियता रसातल में जाती है, वह राष्ट्रविरोधी जुनून पैदा करके अपना जनाधार बनाने का दुष्प्रयास करता है। १५ अगस्त, १९८५ को वहां पाकिस्तानी ध्वज फहराये गये और 'पाकिस्तान पाइंदाबाद' तथा 'भारतीय कुत्तों वापस जाओ' के नारे लगाये गये। १९८६ में गणतंत्र दिवस के दिन भी राष्ट्रविरोधी नारे लगे थे और लगभग ५०० लोगों को हिरासत में लेना पड़ा था। यह

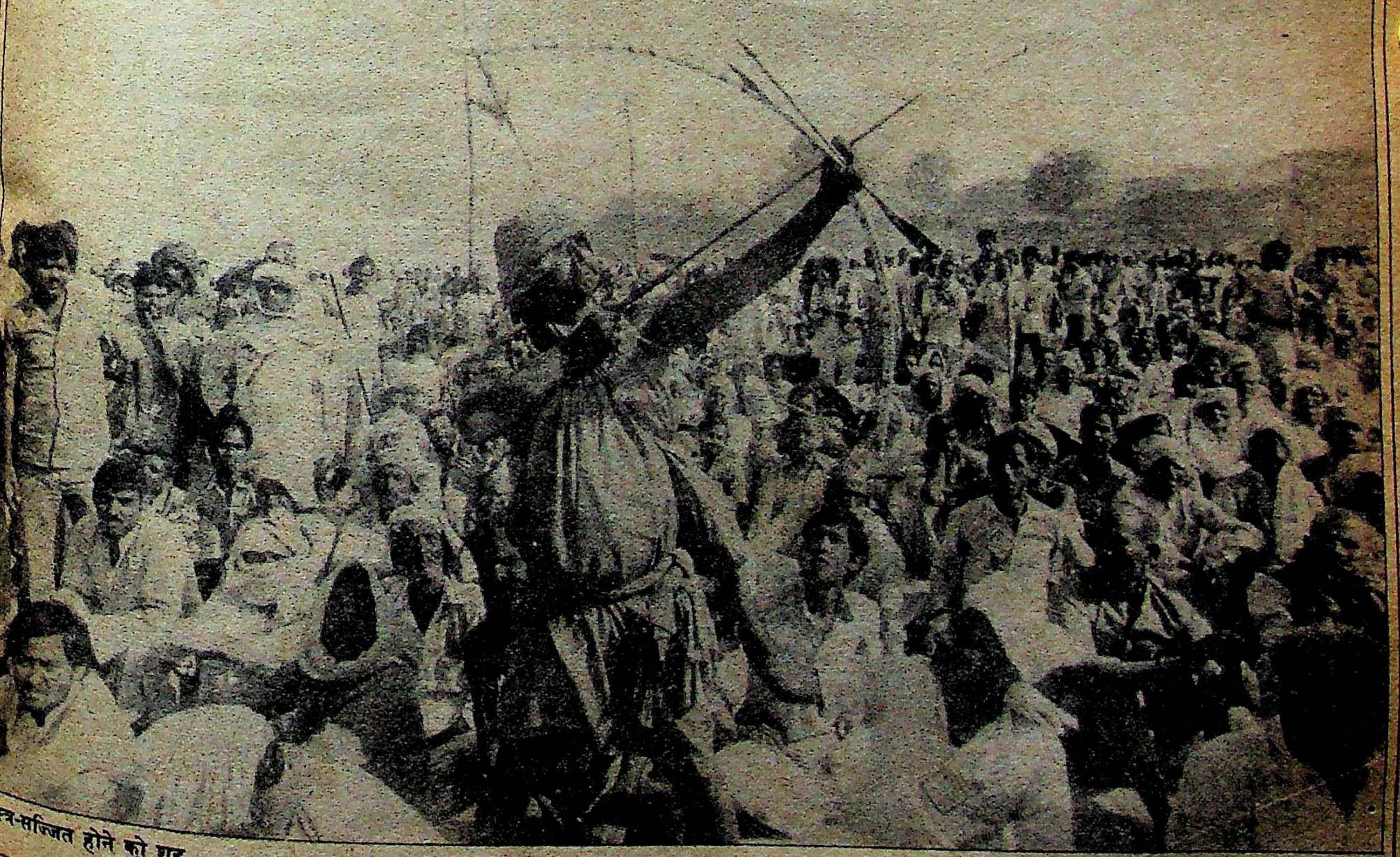

शस्त्र-सज्जित होने को शह

छाया: एस०पी० [illegible]

साक्षात्कार/शंकराचार्य (पुरी)

सरकार हिन्दू धर्म की उपेक्षा कर रही है

१९६४ में जब से जयपुर के संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो॰ चंद्रशेखर द्विवेदी ने पुरी के गोवर्धन मठ की गद्दी संभाली है, तब से ही वह अनेक विवादों के केंद्र बने हुए हैं। उनके पट्टशिष्य सर्वेश्वर ब्रह्मचारी की नजर में 'वह केवल अपने धर्म के लिए' विवादास्पद हैं। प्रो॰ द्विवेदी अब निरंजन देवतीर्थ स्वामीजी महाराज के रूप में जाने जाते हैं। वह पुरी के १४४ वें शंकराचार्य हैं। देश के अन्य तीन शंकराचार्यों की तुलना में वह हिंदू धर्म को 'शुद्ध' बनाये रखने के लिए सबसे ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। राजनीति से लेकर धर्म तक, कोई भी मुद्दा हो, वह बेझिझक तिक्त से तिक्त टिप्पणियां करने में नहीं चूकते। यद्यपि धर्म उनका प्रिय क्षेत्र है, लेकिन राजनीति को वह इसलिए नहीं बख्शते, क्योंकि इसके और धर्म के रिश्ते को वह अवांछित मानते हैं। वह बरजते हैं, "राजनीतिबाजों को धर्म में हस्तक्षेप करना तुरंत बंद करना चाहिए।" यही कारण है कि वह राज्य और केंद्र सरकारों के कोपभाजन बने हैं। जब उड़ीसा सरकार ने सातवें दशक में धर्म-संस्थाओं की भूमि का अधिग्रहण किया और संस्थाओं को सरकारी कोष से चलाने का निर्णय लिया, तो इसके खिलाफ आवाज उठानेवाले स्वामीजी पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सरकारी सहायता को ठुकरा दिया और तब से वह अपने विराट प्रतिष्ठान को अपने धनी भक्तों के दान से चला रहे हैं। उड़ीसा की अध्यात्मनिष्ठ राजधानी—पुरी के पंडितों को स्वामीजी का जब यह कदम पसंद नहीं आया और जब उन्होंने उनका साथ देना बंद कर दिया, तो स्वामीजी ने 'मुक्ति मंडप' के आयोजनों में भाग लेना बंद कर दिया। 'मुक्ति मंडप' पंडितों की ऐसी संस्था है जो अब भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों की नियंता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वामीजी के चर्चित होने का कारण है, उनका गो-हत्या, विधवा-पुनर्विवाह और बाल-विवाह के विरुद्ध धर्म-युद्ध। अब वह सती के पक्ष में झंडा उठाये हुए हैं। वाराणसी के निकट कार दुर्घटना में घायल होने के बाद पुरी के मठ में स्वास्थ्य-लाभ कर रहे शंकराचार्य से प्रकाश नंदा की बातचीत के अंश :

मायाः सामाजिक और राजनीतिक मामलों के बारे में दिये गये तीखे बयानों के कारण आप विवादों के केंद्र में हैं। कैसा लगता है, यह सब आपको ?

स्वामीजी : मैं जो कुछ कहता हूं, उस पर मेरा पूरा विश्वास है। अगर इसके लिए मैं विवादास्पद होता हूं, तो मुझे परवाह नहीं।

माया : आप सती-प्रथा के इतने कट्टर समर्थक क्यों हैं ?

स्वामीजी : पहले मुझे अपनी वह बात साफ कर लेने दीजिए, जो समाचार माध्यमों में नहीं आ सकी है। मैं किसी महिला को जबरदस्ती सती करने के बिलकुल विरुद्ध हूं। लेकिन यदि वह स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेगी, तो मैं उसका समर्थन करूंगा।

माया : क्या आप इसे अमानवीय नहीं मानते ?

स्वामीजी : सती, धर्म है न कि कोई प्रथा और सरकार प्रथा पर रोक लगा सकती है, धर्म पर नहीं।

माया : इतिहासकारों के अनुसार सती-प्रथा कोई धार्मिक कार्य नहीं है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के कारण मध्यकाल में इसका जन्म हुआ। अतः इस संदर्भ में आज सती की क्या प्रासंगिकता है ?

स्वामीजी : यह हमारा धर्म है। ऋग्वेद में सती संबंधी दो मंत्र हैं। एक मंत्र के अनुसार 'सती' अगले जन्म में कभी विधवा नहीं होती और देवी का दर्जा प्राप्त करती है। दूसरे मंत्र के अनुसार, यदि कोई स्त्री 'सती' होने के लिए तैयार नहीं होती, तो रिश्तेदारों को उसे पति की चिता से वापस लाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। अतः यह तय है कि 'सती' को धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है।

माया : तो क्या आप धार्मिक स्वीकृति प्राप्त हर प्रथा को जारी रखने की सलाह देते हैं ?

स्वामीजी : हां, क्यों नहीं ! कम-से-कम सभी सच्चे हिंदुओं को तो जरूर ऐसा करना चाहिए।

माया : आपकी दृष्टि में सच्चे हिंदू कौन हैं ?

स्वामीजी : वे, जो वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत का पालन करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे, एक सच्चा मुसलमान कुरान में कही गयी और एक ईसाई बाइबिल में कही गयी बातों का पालन करता है। एक सच्चा हिंदू वह है, जो शास्त्र में कही गयी बातों का पालन करता है।

माया : आपकी नजर में ऐसे कितने सच्चे हिंदू होंगे ?

स्वामीजी : मुझे यह कहते हुए दुख है कि ऐसे हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

माया : ऐसा क्यों ?

स्वामीजी : क्योंकि सरकार हिंदू धर्म की उपेक्षा कर रही है और राजनेता पश्चिमी विचारों की पूजा में लगे हैं। यह बहुत बुरा है, वे लगातार हिंदूवाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

माया : क्या आप 'सती-प्रथा' की भर्त्सना और उसके खिलाफ जारी अध्यादेश के संदर्भ में ऐसा कह रहे हैं ?

स्वामीजी : सती तो केवल एक घटना है। वैसे भी, सती के बारे में सरकारी रवैया पाखंडपूर्ण है।

माया : कैसे ?

स्वामीजी : दो तरह से। एक, आलोचकों का कहना है कि 'सती' किसी को जिंदा जलाने के समान घृणास्पद कार्य है। मैं उनसे पूछता हूं कि रोजाना गर्भपात के जरिये होने वाली भ्रूण हत्याओं की वे किस तरह निंदा करेंगे? क्या भ्रूण हत्या निंदनीय नहीं है? दूसरी बात यह है कि सरकार ने सभी नवयुवतियों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे जाति, धर्म या परिवार की इच्छा के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में वही सरकार किसी लड़की को पति की मृत्यु के बाद सती होने से कैसे रोक सकती है?

माया : केवल राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ही सती-प्रथा की निंदा नहीं की है, धार्मिक नेता भी इस कार्य में शामिल थे।

स्वामीजी : वे धार्मिक नेता हैं ही नहीं।. वे केवल इतना जानते हैं कि किस तरह भारत सरकार और उसके नेताओं को संतुष्ट किया जा सकता है।

माया : आप कांची के शंकराचार्य और अक्तूबर में उनके द्वारा घोषित योजना के बारे में क्या सोचते हैं।

स्वामीजी : वह राजीव गांधी के गुलाम हैं और उनकी योजनाएं हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ करने की चुनौती देता हूं। लेकिन मै जानता हूं, वे ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल, कांची के शंकराचार्य ने समाज-सुधार के कार्यक्रम की शुरुआत जिस ढंग से की है, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने कांची में कोई मठ स्थापित नहीं किया था। अत:, हम चारों शंकराचार्य (पुरी, बदरीनाथ, द्वारका, शृंगेरी) उन्हें मान्यता नहीं देते। यदि उन्होंने कुछ कहा भी है, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

माया : क्या चारों शंकराचार्य सभी मुद्दों पर एकमत रहते हैं?

स्वामीजी : यह जरूरी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ किये जा रहे षड्यंत्रों से हम सभी चिंतित हैं।

माया : क्या आप लोगों ने इस 'संकट' से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार की है?

स्वामीजी : अभी तक तो नहीं, मगर जल्दी ही इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग मिलेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पिछले कुंभ मेले के दौरान काम शुरू कर दिया था। हरिद्वार में उस दौरान मैंने सभी हिंदू महंतों, मंडलेश्वर और संतों को बुलाकर 'संत समिति' गठित की थी।

माया : इस समिति के उद्देश्य क्या हैं?

स्वामीजी : इसके तीन उद्देश्य हैं। हम भारत सरकार से गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, देश और विदेश में हिंदुओं की हत्याएं रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने और सभी धर्मों के लिए एक समान आचार संहिता लागू करने की भी मांग करते हैं। सरकार हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून नहीं बना सकती। सभी भारतीयों के लिए कानून एक से होने चाहिए।

माया : यह अंतर कहां हैं?

स्वामीजी : जरा शाहबानो के मामले में सरकार की भूमिका पर गौर कीजिए।

माया : क्या आप सोचते हैं कि सरकार आपकी मांगों को स्वीकार कर लेगी?

स्वामीजी : वह मान ले तो बेहतर है। यदि सरकार राजी नहीं होगी, तो 'संत समिति' दूसरा रवैया अपनायेगी, जिसे संभालना उसके बस के बाहर होगा। मेरा यह अल्टीमेटम राजीव गांधी तक पहुंचा दें। इस समय हम अपने कार्यक्रम पर ठीक से विचार कर रहे हैं और इसे मैं आपको भी नहीं बता सकता।

माया : क्या आपकी समिति अकेले यह काम करेगी?

स्वामीजी : नहीं। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मेरे साथ हैं।

माया : क्या आप यह नहीं सोचते कि आपकी योजना और आपके सहयोगी घोर सांप्रदायिक हैं?

स्वामीजी : कैसे? मैं अपने धर्म के हित के लिए काम कर रहा हूं न कि किसी धर्म के खिलाफ। क्या यह सांप्रदायिकता है? इस देश में केवल राजनेता सांप्रदायिक हैं। मेरे जैसे गुरु नहीं।

माया : राजीव गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं।

स्वामीजी : वह भारत के सर्वाधिक सांप्रदायिक प्रधानमंत्री हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है कि अपनी कुरसी को बचाने और अल्पसंख्यकों के वोट हथियाने के लिए वह हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

माया : लेकिन क्या आप हिंदू पुनर्जागरण का काम नहीं कर रहे हैं?

स्वामीजी : हां, और मुझे इस पर गर्व है। मैं अपनी अंतिम सांस तक हिंदू धर्म के उत्थान के लिए लगा रहूंगा।

माया : लेकिन आपके कार्यक्रमों से क्या देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र और सांप्रदायिक सद्भाव को हानि नहीं पहुंचेगी?

स्वामीजी : नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मेरे आदर्श भारत में अल्पसंख्यक भी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार रखेंगे। हिंदुओं को अपने मंदिरों की तरह चर्च और मस्जिदों से भी प्यार करना चाहिए। साथ ही मुस्लिमों और ईसाइयों को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा एक तरफा हो रहा है। अल्पसंख्यक हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं और सरकार उनको बढ़ावा दे रही है।

माया : लेकिन क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि आपके ये कार्यक्रम देश को मध्यकाल की तरफ ले जायेंगे?

स्वामीजी : वाकई मुझे इससे बहुत दुख पहुंचता है कि तुम्हारे जैसे नौजवान पश्चिमी संस्कृति से अंधे हो गये हैं। आप जैसे लोग यह महसूस क्यों नहीं करते कि पश्चिम के लोग अपने धर्म के लिए मर मिटेंगे? यह हाल मुसलमानों का है। ये केवल आधुनिक हिंदू हैं जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करते। मेरा संदेश केवल यह है कि जब 'मुसलमान और ईसाई अपने धर्म पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं तो हिंदुओं को भी उनसे पीछे नहीं रहना चाहिए।'

माया : क्या आपको अपने मिशन में सफलता मिलने की उम्मीद है?

स्वामीजी : हां, पूरी उम्मीद है। यह सच है कि इस समय देश में सच्चे हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन वे फिर भी शक्तिशाली हैं। यह बात सती की घटना के दौरान राजस्थान में सिद्ध भी हो चुकी है। बस उन्हें प्रेरित करने भर की जरूरत है। हम बहुत लंबे समय से अंधकार में हैं। तब से, जबसे पश्चिमी लोगों ने भारत आना शुरू किया।

माया : लेकिन बिना सरकारी समर्थन के आप सफल कैसे होंगे?

स्वामीजी : मैं जानता हूं कि सरकार की चुनौती बहुत विकट है। आखिरकार सरकार एक ताकत तो है ही और रेडियो, टी०वी० जैसे माध्यम उसके पास हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी विजय के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूं। हमारा मनोबल ऊंचा है। राजीव गांधी को यह बतला दीजिए। राजीव गांधी को दिया अल्टीमेटम मैं फिर दोहराता हूं।

माया : राजीव गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं?

स्वामीजी : वह भारत के सर्वाधिक सांप्रदायिक प्रधानमंत्री हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है कि अपनी कुरसी को बचाने और अल्पसंख्यकों के वोट हथियाने के लिए वह हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

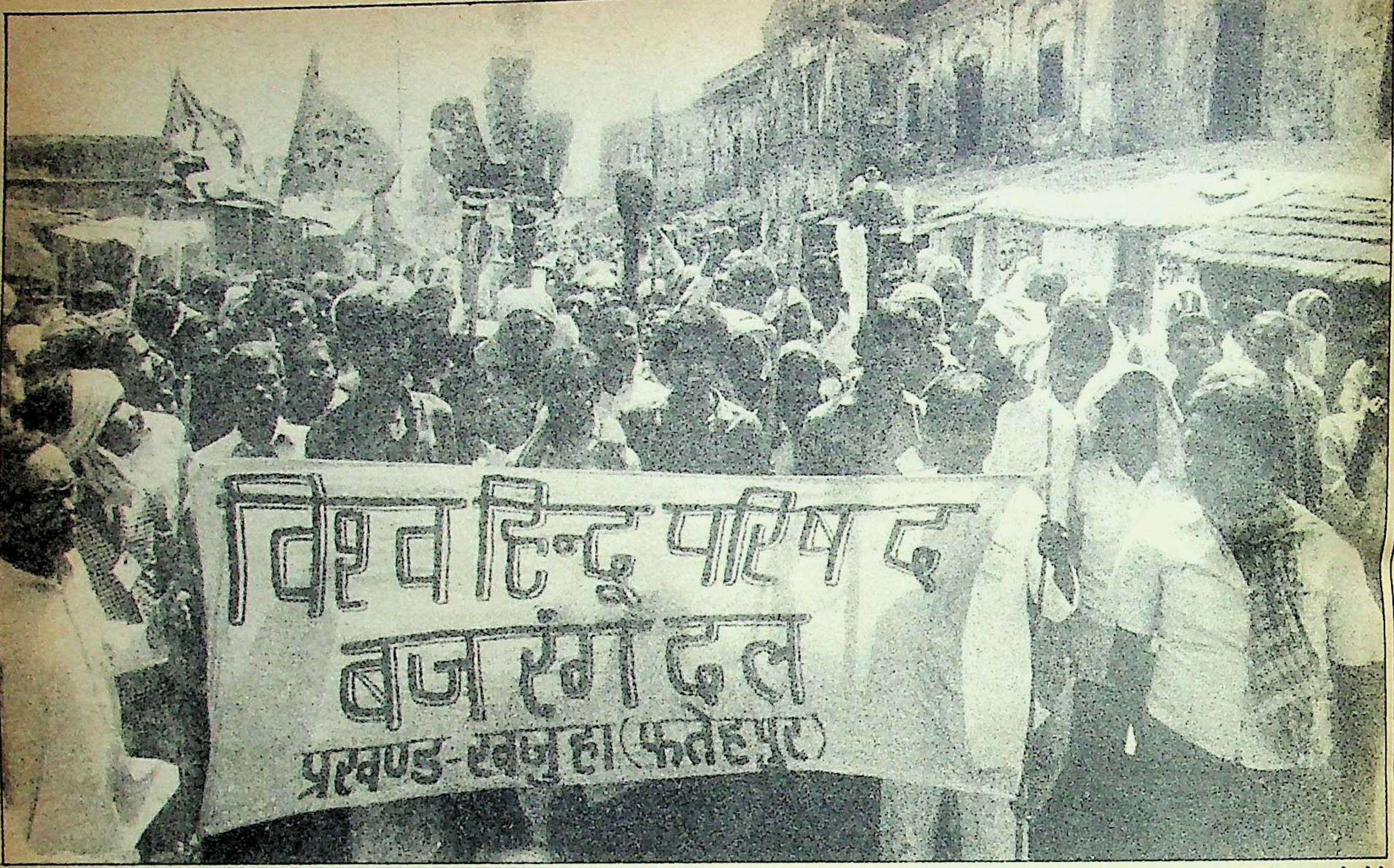

कुकुरमुत्ते की तरह उभरते संगठन

छाया : एस०पी० प्रेमी

प्रक्रिया अब जोरों पर है। सत्ताच्युत गुलशाह तो यहां तक कह रहे हैं कि "मैं पाकिस्तानी हूं।" जब से पंजाब में अलगाववादी भावनाएं फैली हैं, तब से कश्मीर में इस प्रवृत्ति ने और जोर पकड़ा है।

बहुसंख्यकों में सांप्रदायिकता: इन सांप्रदायिक घटनाओं के कारण ही बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं से खेलने के लिए हिंदू पुनरुत्थानवादियों के हौसले बढ़े हैं। जहां तक अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता का सवाल है, अब तक यह कहा जाता था कि यह बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया है। लेकिन अब यह स्थिति उलट गयी है। अब परिषदों, पुरी के शंकराचार्य और गांवों तक पांव पसारने में लगी सेनाओं ने यह गुहार लगाना शुरू कर दिया है कि हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। यह स्थिति किसी भी समय जागृत ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकती है।

जब तक पंजाब में हिंसा नहीं बढ़ी थी, तब तक सांप्रदायिक घटनाएं केवल शहरी इलाकों तक सीमित थीं। यहां तक कि विभाजन के त्रासद दिनों के दौरान भी फिरकेवाराना दंगों की आग नगरों से आगे नहीं बढ़ी। यही कारण है कि बार-बार होने वाले सांप्रदायिक विस्फोटों को देश का ढांचा सहन करने में कामयाब रहा और आग राष्ट्रव्यापी रूप नहीं ले सकी। लेकिन पिछले तीन सालों में पंजाब के आतंकवादी लगातार ग्रामीण अंचलों में पहुंच रहे हैं और खेत मजदूरों तथा गांववासियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इससे निम्न मध्य वर्ग प्रभावित हुआ है, जिसका ग्रामीण भागों से निकट संबंध है। जब शिव सेना ने यह देखा कि असली जनाधार तो ग्रामीण इलाकों में है, तो महाराष्ट्र में शिव सेना ने भी अपने 'सैनिकों' को गांवों में भेजना शुरू कर दिया। बाल ठाकरे इस बात को मानते हैं कि सेना को गांवों में समर्थन मिला है। इसका औचित्य सिद्ध करते हुए वह कहते हैं, "वहां लोग चाहते हैं आक्रामकता, उग्रता। उनको भरोसा है कि केवल शिव सेना ही हिंदुओं की रक्षा कर सकती है।" वह सवाल करते हैं, "क्या आप जानते हैं, गांवों में क्या जहर घोला जा रहा है। शहाबुद्दीन को तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों शहाबुद्दीन उभर रहे हैं।" ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिव सेना 'भगवा सप्ताह' मना रही है। हिंदुओं को गोलबंद करने का कारण है शिव सेना की नजरों का जिला परिषद के चुनावों पर टिका होना।

ठाकरे जैसे लोगों को यह अहसास है कि राजनीतिक प्रभाव से वे धार्मिक उद्देश्य पूरे कर सकते हैं और धार्मिक उद्देश्यों के पूरा होने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसलिए वे धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिये अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें निश्चित सफलता पाने के लिए उनकी कोशिश

ठाकरे जैसे लोगों को यह अहसास है कि राजनीतिक प्रभाव से वे धार्मिक उद्देश्य पूरे कर सकते हैं और धार्मिक उद्देश्यों के पूरा होने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसलिए वे धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिये अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

जागरण या संप्रदायीकरण ?

छाया : राजेन्द्र कुमार

है कि ग्रामीण क्षेत्रों से समर्थन जुटाया जाये। इसी कारण हाल में पनपे शिवशक्ति दल, हिंदू शिव सेना, हिंदू सुरक्षा समिति, बजरंग दल, हिंदू मंच आदि संगठन अपने प्रतीक चिन्ह त्रिशूल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को सक्रिय करने में लगे हैं। इनमें से कुछ संगठन तो पंजाब में भिंडरांवाले के उदय के बाद पैदा हुए हैं। उन पर पाबंदी लगाना भी आसान नहीं है, क्योंकि वे दावा करते हैं कि आतंकवाद और हिंदू विरोधी माहौल के कारण वे आत्मरक्षा में ऐसा कर रहे हैं। इन सेनाओं और इनके शहरी सदस्यों का संबंध जनसंघ, भाजपा और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से रहा है और इन पर अक़सर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। इन संगठनों के प्रति सहानुभूति बढ़ने का मूल कारण हिंदुओं में बढ़ती आक्रामकता है। जो लोग शांतिप्रिय हैं, उनको दूसरे सांप्रदायिक तत्वों और समुदायों से खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए उनका झुकाव भी इन संगठनों की ओर बढ़ता जा रहा है। पंजाब में तो अच्छी-खासी संख्या में महिलाएं हिंदू शिव सेना में शामिल हो गयी हैं। राजनीतिक तत्वों ने जब देखा कि इन संगठनों के पांव जमते जा रहे हैं, तो वे भी या तो प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ हो लिये या फिर गुपचुप इनको समर्थन देना शुरू कर दिया। यह एक प्रकार का विषाक्त चक्र है। जैसे अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना ने मुस्लिम लीग और जमायते इस्लामी जैसे संगठनों को शक्ति प्रदान की थी, ठीक वैसे ही अब शिव सेना और विश्व हिंदू परिषद, दोनों हिंदुओं में बढ़ती असुरक्षा की मनोवृत्ति को भुनाने में लगे हैं। धर्मनिरपेक्षता का दम भरनेवाली कांग्रेस-इ जैसे चुनाव के समय सांप्रदायिक भावनाओं का लाभ उठाती है, वैसे ही हथकंडे ये संगठन भी आजमा रहे हैं।

धर्मांधता का प्रकोप

छाया : राजेन्द्र कुमार

कर्म के सहारे राजनीति : अशोक सिंघल का कहना है कि परिषद ने २०० संवेदनशील जिलों का चयन किया है और उनमें ६००० सदस्यों को काम पर लगा दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है : बाहरी घुसपैठ के शिकार होने वाले सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े वर्ग को लुभाने में लगी ईसाई मिशनरियों से प्रभावित आदिवासी क्षेत्र, भीतरी भाग, जहां अलगाववादी तत्व सक्रिय हैं। यदि चुनाव के समय परिषद को किसी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं मिलता है, तो भी इस तरह की गतिविधियों से एक राजनीतिक आधार खड़ा किया जा सकता है।

कोई संगठन यदि राजनीति की ओर झुकता है, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि इसके पीछे धार्मिक नज़रिया है, तो फिर यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्वास्थ्यकर नहीं कहा जा सकता और न ही उस समुदाय के लिए हितकर है, जिसका समर्थन ऐसा संगठन करता है। स्वयं नानाजी देशमुख मानते हैं कि कट्टरपंथ संहारक होता है। [illegible] इस्लामी देशों का उदाहरण देते हैं, जहां चरमपं[illegible]

के०आर० मल्कानी

हिंदू अन्याय सहन नहीं करता

हिंदुओं में पल रही असुरक्षा की भावना कोई नयी बात नहीं है। यह उतनी ही पुरानी है जितनी कि आजादी और देश-विभाजन। आज यदि यह भावना बहुत तीव्र दिखलायी पड़ रही है, तो इसलिए कि बुद्धिजीवियों का ध्यान इस ओर गया है। बहरहाल, मेरी दृष्टि में हिंदू पुनरुत्थान का जोर सब जगह एक जैसा नहीं है। यह केवल अखबार पढ़नेवाले शहरी लोगों तक सीमित है। यह कहना गलत होगा कि सत्तर करोड़ हिंदू खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शहरी हिंदू यह महसूस कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए उनके अधिकारों से अधिक उनकी खेती, रोटी और रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण है।

शहरी हिंदू यह अनुभव करते हैं कि उनको अनदेखा किया जा रहा है। मेरे खयाल से मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद इस भावना ने जोर पकड़ा है। दक्षिण में सैकड़ों हिंदुओं द्वारा धर्म-परिवर्तन करने की घटना से हिंदुओं को बड़ा सदमा पहुंचा और तभी से उनके मन में यह भावना घर कर गयी है कि हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही ताकतों के कारण यह देश सुरक्षित नहीं है।

आज हिंदू खुद को घिरा महसूस कर रहे है। एक तरफ पडोसी देश पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। सभी अरब देश भी मुस्लिम हैं। अमरीका और इंग्लैंड ईसाई राष्ट्र हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू खुद को कमजोर पाते हैं। वे सोचते हैं कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? शायद 'असुरक्षा' शब्द का इस्तेमाल अति होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू इस बर्ताव को अपने साथ ज्यादती मानते हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि भारत मुख्य रूप से हिंदू देश है। ठीक उसी तरह, जैसे इंग्लैंड ईसाई राष्ट्र है। भारत में अन्य धर्मों को माननेवाले लोग भी हैं, मगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। यह तथ्य हम क्यों नहीं स्वीकार करते? अन्य धर्मानुयायी भी हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक जातियां यह नहीं समझतीं। मुस्लिम, सिख या अन्य किसी भी धर्म के हिंदू विरोधी नहीं हैं।

यदि कहीं उद्घाटन समारोह में हवन होता है या नारियल फोड़ा जाता है, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? यदि टी०वी० और रेडियो पर भजन आते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? यदि अल्पसंख्यक लोग भी इसमें भागीदारी करें, तो मामला इतना तूल न पकड़े। प्रातःकाल पूजा करने से सुखद अनुभूति मिलती है। यह ऐसा कारण नहीं है, जिससे अल्पसंख्यक घबरा रहे हैं। लेकिन मुसलमान इस पर आपत्ति करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों? वे शेर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि एक मुसलमान दस हिंदुओं के बराबर है। तब उन्हें यह महसूस क्यों करना चाहिए कि हिंदुओं के कारण वे खतरे में हैं? दरअसल, हर अल्पसंख्यक जाति आक्रामकता और अन्य बातों का अद्भुत मिश्रण है।

मैं नहीं समझता कि हिंदू सांप्रदायिक होते हैं क्योंकि उन्होंने अन्य धर्मों को दबाने की कभी कोशिश नहीं की। सांप्रदायिकता का मतलब है, किसी अन्य धर्म की कीमत पर अपने धर्म को विस्तार करने की कोशिश, जबकि हिंदूवाद का आधार है सहिष्णुता और उदारता। हिंदुओं को विश्वास है कि उनकी कौम हजारों साल पुरानी है और आगे भी हजारों साल तक जीवित रहेगी। उन्हें विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, उनका धर्म संकट में नहीं पड़ सकता। भारत में इस तरह का विश्वास किसी धर्म में नहीं है। हिंदू समय की कसौटी पर खरा उतरा है। वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। मैं मानता हूं, इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन वे इस सबको भूलने वाले नहीं। पंजाब की घटनाओं से हिंदू और सावधान हुए हैं। यदि कोई हिंदुओं की जान लेगा या उन्हें खदेड़ना चाहेगा, तो निश्चित रूप से उनमें रोष पैदा होगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए दंगों को मैं सांप्रदायिक नहीं मानता। निश्चित रूप से यह राजनीति प्रेरित था। इसे 'हिंदू दंगा' नहीं कहा जाना चाहिए। इस तरह के फसाद करना हिंदू धर्म के खिलाफ है।

इन सबके बावजूद हिंदुओं में किसी हद तक असुरक्षा की भावना भी है। यह इसलिए कि सरकार धर्म निरपेक्षता की नीति का पालन ढंग से नहीं कर रही। मेरे खयाल से तो सरकार यह भी नहीं जानती कि 'धर्म निरपेक्षता' है क्या? वह धर्म निरपेक्षता का मतलब यही समझती है कि हिंदुओं को पूरी तरह से अनदेखा करो और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दो। उन्हें पता है कि बहुसंख्यकों के वोट तो उन्हें मिलेंगे ही, इसलिए वे अल्पसंख्यकों के वोट बटोरने के प्रयास में ऐसा करते हैं।

एक बार यदि हिंदुओं ने यह महसूस कर लिया कि वे असुरक्षित हैं, तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। खासतौर पर मुस्लिम, जो ये समझ रहे हैं कि हिंदू उनके खिलाफ हथियारबंद हो रहे हैं। धर्म निरपेक्षता, मुस्लिम वोट बटोरने की नीति बन गयी है। हर धर्म को बराबर अधिकार देने की बजाय यह वोट बटोरने का साधन बन गयी है और जिससे कोई भी लाभान्वित नहीं हो रहा। सरकार को पता नहीं कि धर्म निरपेक्षता क्या है? उन्हें तो केवल राज करने से मतलब है और इसके लिए वे धर्म का उपयोग कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति उन्हें वोट दिलाती रहेगी। दुख की बात यह है कि हिंदू इस षड्यंत्र के प्रति जागरूक नहीं हैं। एक समय आयेगा जब हिंदू यह सब महसूस करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबा समय ले लेगी।

हिंदुओं को इस सरकार से नाराज होना चाहिए, क्योंकि यह उनकी स्थिति को कमजोर बना रही है। यदि अल्पसंख्यक इस बात पर कोई नाराजगी दिखाते हैं और दिखा भी रहे हैं, तो यह उनके लिए हानिप्रद होगा। वे बराबरी के लिए नहीं कहते। वे अस्सी करोड़ हिंदुओं पर हावी होना चाहते हैं। पढ़े-लिखे हिंदू जागरूक हैं, इसलिए वे मुखर हैं। गांव में रहनेवाले हिंदू ज्यादा जागरूक नहीं हैं। वे कट्टर हिंदू नहीं हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। यदि शहरों में रहनेवाले हिंदू यह महसूस कर लें कि उनके हित खतरे में हैं, तो उनके गुस्से से यह सरकार सुधर जायेगी।

प्रस्तुति : अनिल शर्मा

> **एक बार हिंदुओं ने यह महसूस कर लिया कि वे असुरक्षित हैं, तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। खासतौर पर मुस्लिम, जो ये समझ रहे हैं कि हिंदू उनके खिलाफ हथियारबंद हो रहे हैं। धर्म निरपेक्षता मुस्लिम वोट बटोरने की नीति बन गयी है। हर धर्म को बराबर अधिकार देने के बजाय यह वोट बटोरने का साधन बन गयी है और जिससे कोई भी लाभान्वित नहीं हो रहा।**

सैयद शहाबुद्दीन

'हिंदू सांप्रदायिकता आक्रामक हो गयी है'

कृपया मुझे गलत न समझें। मैं उनमें से नहीं हूं, जो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई फिरकापरस्त नहीं है। सांप्रदायिक तत्व दोनों ही तरफ हैं, लेकिन इसमें एक फर्क है। जब मैं देश के सियासी हालात की तरफ गौर करता हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदू सांप्रदायिकता आक्रामक है। यह श्रीमती इंदिरा गांधी के उदय के साथ ही शुरू हुई। विभिन्न कारणों से श्रीमती गांधी ने इस नये राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। इसकी बदौलत हर समय वह हिंदू सांप्रदायिकता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देती रहीं। हिंदू सांप्रदायिकता हमारे समाज में हमेशा से रही है। यहां तक कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी मौजूद रही, मगर कुछ कारणों से यह उभरकर सामने नहीं आ सकी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सरीखे राष्ट्रीय नेता उस समय काफी जागरूक थे, लेकिन अब लगता है कि उसने केंद्रीय भूमिका प्राप्त कर ली है। जैसाकि मैंने पहले कहा, यह काम इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ और राजीव गांधी के समय भी जारी है। राजीव गांधी को विरासत में प्रधानमंत्री-पद बीच मझधार में नाव की तरह मिला। उस स्थिति में कोई भी नाविक नाव की दिशा बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह इससे जांचा जा सकता है कि १९८४ का चुनाव उन्होंने पूरी तरह से सांप्रदायिक तर्ज पर लड़ा था।

मेरा कहना यह है कि आज हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता में एक खास अंतर है। मुस्लिम सांप्रदायिकता रचनात्मक है। मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं जब सांप्रदायिकता की बात करता हूं, तो मेरा मतलब उस घटना से होता है, जिसमें धार्मिक चेतना और धार्मिक प्रतिरोध, धार्मिक तनाव में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब भी धार्मिक तनाव पैदा होता है, तो कई मर्तबा वह विस्फोट के रूप में सामने आयेगा ही।

इस समय देश की राजनीति में धार्मिक तनाव पैदा हो गया है और यही समय-समय पर विस्फोटित होता है। जब भी दो संप्रदायों के बीच हिंसा होती है, तो उसे संभालने की जिम्मेदारी राज्य के तंत्र पर होती है, क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य के जिम्मे है। लेकिन मुस्लिम नजरिया से आज लगभग हर पुलिस वाला हिंदू है, हर मजिस्ट्रेट हिंदू है। अत: सांप्रदायिक हिंसा का रूप भी बदल गया है। फासीवादी के रूप में सामने आ रही यह सांप्रदायिकता मुख्य रूप से गुजरात सहित हिंदी भाषी राज्यों की समस्या है। गुजरात में सांप्रदायिकता का प्रचार करने वाले आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का अभियान छेड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं। लेकिन यदि गुजरात में सांप्रदायिक दंगे नये हैं, तो इसलिए कि गुजरात मुसलमान कभी राजनीति में नहीं थे।

राजीव गांधी को विरासत में प्रधानमंत्री-पद बीच मझधार में नाव की तरह मिला। उस स्थिति में नाविक नाव की दिशा बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह इससे जांचा जा सकता है कि १९८४ का चुनाव उन्होंने पूरी तरह से सांप्रदायिक तर्ज पर लड़ा था।

देखा जाये तो गैर-मुस्लिमों के बनिस्बत ज्यादातर मुस्लिम शहरी हैं। यह गौर करने वाली बात है कि सांप्रदायिक हिंसा ज्यादातर शहरों में ही दिखायी देती है। बहरहाल, यह दुखद स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, यदि संप्रदायों का अनुपात संतुलित हो। यदि यह अनुपात ९०:१० का है, तो एक संप्रदाय दूसरे पर पूरी तरह हावी रहेगा। दूसरा संप्रदाय भी हर बेइज्जती को बर्दाश्त करता जायेगा। यह सुरक्षा का मनोविज्ञान है, लेकिन जब अनुपात ६०:४० का होगा, तो दूसरा संप्रदाय यह जरूर सोचेगा कि उसे क्यों दबना चाहिए? यह टकराव का मनोविज्ञान है। और ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक दंगे जन्म लेते हैं।

जब पिछले अनुभवों को हम देखते हैं, तो पता चलता है कि सांप्रदायिक हिंसा में बहनेवाले नब्बे प्रतिशत मुसलमान होते हैं, नष्ट होने वाली संपत्ति का नब्बे प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का होता है, जेल में बंद होने वाले लोगों में भी नब्बे प्रतिशत मुसलमान ही होते हैं, तो क्या मुसलमान आत्महंता ग्रंथि से ग्रस्त हैं? हम एक ऐसी हालत में पहुंच गये हैं, जहां सांप्रदायिकता की दृष्टि से ही नहीं, हर दृष्टि से एक नागरिक के नाते हम महसूस करते हैं कि सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गयी है।

बहरहाल, सरकार में परिवर्तन से समस्या का समाधान नहीं होगा। नये मापदंडों के तहत राजकीय मशीनरी को पुनर्गठित करना होगा। जो समाज के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सके। लोगों को फिर से शिक्षित करना होगा। आखिरकार, समस्या की वास्तविक जड़ें धार्मिक चेतना में ही हैं। कट्टरवाद और धर्मोन्माद ने आज एक भय के कारण हिंदुओं के दिमाग में कब्जा कर लिया है। आप अखबारों में छप रहे लेखों का विश्लेषण कीजिए। आप ऐसे समाचार पायेंगे, जिनमें छपा होता है कि 'मुस्लिम आज भी इस देश में राज करने का सपना देख रहे हैं,' क्योंकि यहां प्रजातंत्र है, हर रोज प्रेस में छपता है कि मुसलमान षड्यंत्र रच रहे हैं। यह कुप्रचार इस प्रकार किया जा रहा है: "मुसलमान जानबूझकर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या के बल पर ही वे अधिकार पा सकते हैं। पड़ोसी देशों से भी मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। वे बहुविवाह करके रात दिन बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे परिवार नियोजन का बहिष्कार कर रहे हैं और यहां तक कि पेट्रोडालर के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं।" यह भी कहा जा रहा है कि अगले पचास सालों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। इस सबके चलते हिंदुओं में भय व्याप्त हो गया है और उनकी आक्रामकता का कारण भी यही भय है।

इस तरह का भय शिक्षा के द्वारा पैदा होता है। इतिहास जैसे विषयों में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान हमलावर थे और उन्होंने हिंदुओं पर शासन किया था। भय फैलने का दूसरा कारण मीडिया है। आखिर वे क्या दर्शा रहे हैं? जरा फिल्मों और कार्टूनों पर गौर कीजिए। उनमें हिंदू और मुसलमान किस तरह दिखाये जाते हैं? किसी मुसलमान से हिंदू के बारे में पूछेंगे, तो वह कहेगा, 'अरे, वे तो लालची होते हैं।' इसी तरह जब किसी हिंदू से मुसलमानों के बारे में पूछेंगे, तो वह कहेगा "वे तो पैदाइशी धर्मान्ध होते हैं।" अत: एक बुरी छवि दोनों संप्रदायों के दिमाग में एक दूसरे के बारे में बन गयी है। ऐसे में एक दूसरे को हम कैसे समझ सकते हैं?

प्रस्तुति: प्रकाश

घातक द्वंद्व उत्पन्न किया है। वैसे भी जहां धर्मान्धता होती है, वहां सभी धर्मों पर चोट पहुंचती है, क्योंकि इससे तार्किकता नष्ट होती है और आस्था की जड़ें उखड़ती हैं। हालांकि वह हिंदुओं में हाल में पनपी पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को धर्मविश नहीं मानते। उनकी दृष्टि में यह हिंदू संस्कृति के प्रति चेतनता है। वह कहते हैं, "हिंदू स्वभाव से सहिष्णु है, प्रतिक्रियावादी नहीं।" लेकिन सुब्रह्मण्यम स्वामी को इसमें फासीवाद की बू आती है। वह चेतावनी देते हैं, "अगर उदार लोग आगे आकर धर्मांध लोगों के शिकंजे से समुदाय को नहीं निकालेंगे, तो समुदाय पर फासीवादियों का कब्जा हो जायेगा। इस समय हिंदुओं में जो चेतना बढ़ रही है, वह नकारात्मक और अधोगामी है। यह दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति तीव्र घृणा को जन्म दे रही है, जिससे और ज्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है और फूट पड़ रही है।"

वह कहते हैं कि त्रिशूल के नाम पर सिखों पर हमले करने का मतलब है और अधिक खतरे को न्योता देना। सिख भी हिंदू हैं, लेकिन "यदि वह हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते, तो हम लोगों को इस बहादुर समुदाय का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उनके गुरुओं ने हिंदुओं के लिए काफी बलिदान किया है। गुरुतेगबहादुर और उनके पुत्र गुरु गोविन्द सिंह ने हिंदुओं की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उसको सच्चा हिंदू कैसे भूल सकता है।"

लेकिन ये सारी बातें भुलायी जा रही हैं। वह कहते हैं, "मैं कुछ हिंदुओं से मिला हूं जो सोचते हैं कि दिल्ली, कानपुर, इंदौर तथा अन्य शहरों में गुमराह भीड़ ने जो सिखों की निर्मम हत्याएं की हैं, वे श्रीमती गांधी की हत्या का सही जवाब था।" इसी का परिणाम है कि कुछ सिखों ने पंथ के नाम पर यह प्रण कर रखा है कि जिन राजनीतिक लोगों पर हत्यारी भीड़ का नेतृत्व करने का संदेह है, उनको वे नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतिशोधात्मक हत्याएं अंततः हिंदू धर्म को कमजोर करेंगी। यदि हिंदू धर्मांध होंगे, तो अन्य धर्मांध धड़ों के साथ टकराहट होगी और इसका परिणाम त्रासद होगा।

विभाजन के घावों के भरने के बाद हिंदू और मुस्लिम एक हद तक सामान्य स्थिति में आ गये थे। हालांकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती रही हैं, लेकिन १९७७ से यह सिलसिला तेज हो गया। १९७७ में जहां १८८ घटनाएं हुई थीं, वहां १९८५ में ५२५ तक पहुच गयीं। इनमें पंजाब की घटनाएं शामिल नहीं हैं। जब से वहां समस्या बढ़ी है, तब से हिंदू उग्रवाद तेजी से बढ़ा है। विभिन्न सेनाओं की सदस्य संख्या ५०,००० को पार कर गयी है। जब चुनाव का बुखार राजनेताओं पर चढ़ेगा, तो जाहिर है कि इन सेनाओं का महत्व उनकी दृष्टि में बढ़ेगा। यही कारण है कि पुरातनवादियों की भर्त्सना करने की हिम्मत बहुत कम राजनेता कर पा रहे हैं। स्वामी कहते हैं, "यहां तक कि श्रीमती गांधी ने भी कभी मुकाबला नहीं किया।" वह याद दिलाते हैं कि एक बार श्रीमती गांधी को पुरी के मंदिर में यह कह कर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी कि वह हिंदू नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इसका विरोध नहीं किया। वामपंथियों ने भी केरल के चुनाव में विवेकानंद के संदर्भों का इस्तेमाल किया था। यद्यपि वहां साक्षरता काफी है और लोग धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के हैं, लेकिन फिर भी मतदाताओं को धार्मिक प्रतीकों से लुभाया गया। पंजाब में भी समस्या इसलिए जटिल हुई कि वहां धर्म और राजनीति का घालमेल किया गया।

त्रिशूलों की बाढ़

राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला कौन था? वह हिंदू था। तो जब सारे हिंदुओं को हत्यारा नहीं कहा जा सकता, तो फिर दो रक्षकों और मुट्ठी भर आतंकवादियों के काले कारनामे समुदाय पर कैसे थोपे जा सकते हैं?

साधु-संतों का बढ़ता प्रभाव

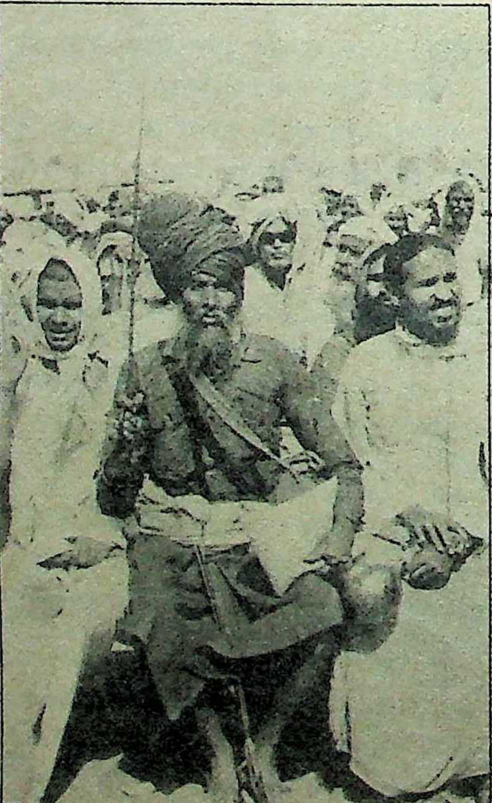

अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के और उग्र होने की आशंका है, क्योंकि राजीव गांधी के तीन साल पूरे हो रहे हैं और राजनेताओं के दिमाग में अगला चुनाव जीतने का भूत सवार है। दूसरी ओर धर्मांध लोग भी मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। वे अपनी गतिविधियां बढ़ायेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजनेता उनको तुष्ट करने के लिए उनके सामने झुक सकते हैं। यही कारण है कि हिंदू उग्रवाद को हवा मिल रही है। सुब्रह्मण्यम स्वामी की राय में, "पहचान का कोई संकट नहीं है, लेकिन क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद और जातिवाद के बढ़ने के कारण हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।" यह विभ्रम उन सेनाओं के इस प्रचार से और बढ़ रहा है कि पंजाब में उनका अस्तित्व खतरे में है। वैसे देखा जाये, तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उससे हिंदुओं को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। जिस समुदाय की संख्या ६० करोड़ हो, क्या उसे मुट्ठीभर आतंकवादी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यदि दो गुमराह सिख रक्षकों ने प्रधानमंत्री की हत्या करके समुदाय और देश का सिर नीचा किया है, तो ऐसे भी सैकड़ों उदाहरण हैं जब सिखों ने अपनी बहादुरी से देश का नाम रोशन किया है। फिर राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला कौन था? वह हिंदू था। तो जब सारे हिंदुओं को हत्यारा नहीं कहा जा सकता, तो फिर दो रक्षकों और मुट्ठीभर आतंकवादियों के काले कारनामे सारे समुदाय पर कैसे थोपे जा सकते हैं? सिखों को भी ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। जिस तरह से उन्होंने १९४७-४८ में लाहौर में हुई घटनाओं को मन से निकाल दिया है, उसी तरह १९८४ के दंगों के घावों को भी भरने का प्रयास करना होगा। उनको उन मुट्ठीभर आतंकवादियों का विरोध करना होगा जो निर्दोष लोगों की हत्या में लगे हैं। जहां तक हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू संस्कृति में समन्वय और प्रतिरोध की पर्याप्त शक्ति है। वैसे भी हिंदू धर्म, धर्म से ज्यादा एक जीवन शैली है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता सहिष्णुता है और सहिष्णुता से सहिष्णुता का जन्म होता है। बंबई के माटुंगा में आज भी इसे देखा जा सकता है। वहां यदि पंडित को बाहर जाना होता है, तो बगल की मस्जिद के मौलवी पर मंदिर की देखभाल का भार छोड़ जाता है और ऐसा ही मौलवी भी करता है। सहअस्तित्व की भावना में ही सुरक्षा का रहस्य है और इस रहस्य को जानने की आज सख्त जरूरत है अन्यथा अलग-अलग धर्मों के तथाकथित झंडाबरदार धर्मों को तो नष्ट करेंगे ही उनके अनुयायियों को भी आपस में भिड़ा कर सर्वनाश कर देंगे।

—विजय दत्त

साक्षात्कार/अशोक सिंघल

हिन्दू जागरण का सैलाब आने वाला है

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातुकर्मी इंजी॰ की शिक्षा प्राप्त अशोक सिंघल ६१ वर्ष के हैं। इस उम्र में व्यक्ति स्वभावतः ठंडा हो जाता है, लेकिन श्री सिंघल आवेश में हैं। उनका गुस्सा किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार जिस तरह हिंदुओं के साथ व्यवहार कर रही है, वह उससे नाराज हैं। उनकी मान्यता है कि हिंदुओं के साथ समानता और न्याय के आधार पर व्यवहार नहीं हो रहा है। वह हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। अधिकांश लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से उनके संबंधों के कारण उन्हें घोर सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन उनका दावा है कि हिंदू सांप्रदायिक नहीं होता और न ही रूढ़िवादी। दूसरी सांस में वह हिंदुओं के महा जनजागरण की चेतावनी भी देते हैं जो सभी राजनीतिक दलों को आत्मसात कर लेगा। उनकी दृष्टि में २१वीं शताब्दी का हिंदू नया हिंदू होगा जो अपराजेय होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय से ताजा-ताजा विचार-विमर्श करके लौटे अशोक सिंघल से रंजना कक्कड़ ने हिन्दू-आक्रोश से संबंधित 'विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश:

माया: हिंदुओं में कुछ हद तक नाराजगी बढ़ रही है। क्या आप खुद को 'क्रुद्ध हिंदू' कहेंगे?

सिंघल: मैं नहीं कह सकता कि मैं क्रुद्ध हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में क्रोध को कोई स्थान नहीं है। लेकिन हिंदू जरूर यह अनुभव करते हैं कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। यह मूलतः हिंदुओं का देश है। यदि अपनी मातृभूमि में ही उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, तो न्याय पाने के लिए वे कहां जायेंगे? यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। इन अर्थों में हिंदुओं में कुछ नाराजगी है?

माया: वे क्यों नाराज हैं?

सिंघल: क्योंकि भारत का विभाजन हो जाने और पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद भी हिंदू—मुस्लिम विवाद के मुद्दों को दूर नहीं किया गया। हिंदु समुदाय का धैर्य उस समय जवाब दे गया, जब १९८१-८२ में मीनाक्षीपुरम में सामूहिक धर्मांतरण हुआ और यह रहस्योद्घाटन हुआ कि आठ करोड़ हरिजनों को धर्मांतरित करने की योजना बनी है। यह हिंदुओं के लिए असहनीय था। इसी प्रकार बंगलादेश से प॰ बगाल, असम और बिहार में जब मुसलमानों की घुसपैठ हुई, तो इंदिरा गांधी सहित हमारे राजनेताओं ने सोचा कि ये शरणार्थी कांग्रेस के मतदाता साबित होंगे। तब इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों ने इंदिरा गांधी से सौदेबाजी की और सिर्फ एक मुद्दे पर यह तय हुआ कि जो मुस्लिम शरणार्थी भारत के प्रति निष्ठावान होंगे, उन्हें वापस नहीं भेजा जायेगा। वस्तुतः हिंदुओं को इन घुसपैठियों को भारत में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, खासकर पाकिस्तान बनने के बाद। वैसे स्वयं पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इस्लामिक देशों से आ रहीं पैट्रो-डालर की बाढ़ के खिलाफ भी काफी शोर मच रहा है। ईसाइयों को भी विदेश से दान के रूप में धन मिल रहा है। यदि यह छोटी-मोटी रकम होती, तो चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा धन प्राप्त करनेवाली संस्थाओं की संख्या करीब दस हजार है जो विदेश से सालाना ४३४ करोड़ रुपए प्राप्त करती हैं—अर्थात भारत के हर जिले के लिए एक करोड़ रुपए विदेश से आते हैं और यही धन भारत के मुसलमानों और ईसाइयों के बैंकों में जमा हो जाता है, जिसका वे धर्मांतरण में इस्तेमाल करते हैं। यह अनपेक्षित नहीं है कि इससे हिंदुओं में असंतोष पनप रहा है।

माया: अतः आप सहमत हैं कि हिंदुओं में नाराजगी है?

सिंघल: मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि हिंदुओं ने कभी अपने अधिकारों की मांग नहीं की, लेकिन अब वे मुखर हो रहे हैं।

हमने सुना है कि जयेंद्र सरस्वती ने अपने मठ और पारंपरिक पूजा का परित्याग कर दिया है। यह सब उन्होंने केवल हिंदू समाज की सेवा के लिए किया है। मैं समझता हूं कि न केवल जयेंद्र सरस्वती, बल्कि सभी धार्मिक नेता संकट की घड़ी में हिंदू समाज की सेवा के लिए आगे आयेंगे।

माया: इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू अब जागरूक हो रहे हैं?

सिघल: स्वाभाविक रूप से। हिंदू समझते हैं कि उनके नेता ही उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, जिनके लिए धर्म-निरपेक्षता का मतलब मुसलमानों और ईसाइयों का तुष्टीकरण है, जबकि ये अल्पसंख्यक हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, सभी धर्मों के बीच समानता और सद्भावना। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। हमारे नेता अल्पसंख्यकों से मित्रता स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन यह मित्रता खरीदी नहीं जा सकती, यह तो भावनात्मक लगाव से ही संभव है, जबकिं हमारे नेता इसे खरीदने के अभ्यस्त हैं। पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार करके हमारे नेताओं ने वास्तव में मुसलमानों से मित्रता खरीदी थी, जबकि मुसलमान इससे संतुष्ट नहीं थे। वे इस देश और यहां के लोगों को भी बांटना चाहते थे। दुनिया में यही एकमात्र देश ऐसा है, जहां के नागरिकों के लिए समान कानून नहीं हैं। क्या यह मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं है कि उन्हें अपना व्यक्तिगत कानून अलग रखने की इजाजत दे दी गयी है। उदाहरण के तौर पर मुसलमान 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' में हिस्सा नहीं लेते, जबकि देश को इसकी बेहद जरूरत है।

माया: धर्मनिरपेक्षता की आपकी परिभाषा क्या है?

सिंघल: 'सर्वधर्म समभाव'। हिंदुओं ने कभी इस बात की वकालत नहीं की कि राजसत्ता किसी धर्म-संप्रदाय को प्रोत्साहित करे। हिंदुओं में १२० धार्मिक संप्रदाय हैं और राज्य सत्ता के लिए यह जरूरी है कि वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे। हिंदुओं के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी संप्रदायों के प्रति समान आदर भाव रखना। केवल अशोक ही एकमात्र ऐसा सम्राट हुआ है, जिसने किसी विशेष संप्रदाय को प्रश्रय दिया। अन्यथा कोई राजा ऐसा नहीं हुआ, जिसने किसी संप्रदाय विशेष को प्रोत्साहित किया या उसे अपना राजधर्म बनाया।

माया: क्या आप मूल रूप से धर्म-निरपेक्षता की इस धारणा से सहमत हैं?

सिघल: हां, धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ है, लेकिन इन अर्थों में इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ?

माया: ऐसा क्यों है कि अपने प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध हिंदुओं को आजादी के चालीस साल बाद गुस्सा आ रहा है?

सिघल: क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता जैसे शब्दों के अर्थों में भी इस दौरान काफी अंतर आ गया है।

माया: पिछले ५-१० सालों में ऐसा क्या हुआ, जिससे हिंदुओं में व्यापक रूप से असंतोष फैला।

सिंघल: हां, धर्मांतरण और घुसपैठ के साथ-साथ केरल और आंध्र प्रदेश ने हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया। जिसके कारण हिंदू यह सोचने लगे कि सरकार केवल मंदिरों का ही अधिग्रहण क्यों करती है, गिरजाघरों और मस्जिदों का क्यों नहीं? इससे हिंदू समाज हिंदू मंदिरों की संपदा का अपने हित में प्रयोग नहीं कर सकता, यह लालची राजनेताओं के हाथों में बनी रहेगी। हिंदू अधिक समय तक अन्याय सहन करने के लिए तैयार नहीं है।

माया: क्या शहरी हिंदू अचानक पहचान के संकट से पीड़ित हो गये हैं?

सिंघल: हां, शहरी और ग्रामीण-दोंनों हिंदू। हमें इनमें भेद क्यों करना चाहिए?

माया: क्योंकि ग्रामीण हिंदू हमेशा से परंपरावादी रहा है, लेकिन अब पाश्चात्य सभ्यता को अपना लेनेवाले शहरी हिंदू भी अपने धर्म के प्रति चिंतित हो गये हैं।

सिंघल: यकीनंन ग्रामीण हिंदू जानकार नहीं है। वह नहीं जानता कि इस देश में क्या हो रहा है, और इसी कारण उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन शहरी शिक्षित हिंदू यह अनुभव करता है कि शीघ्र ही उसके सामने इन दो बातों के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जायेगा—या तो पूरे हिंदू समाज को संगठित करो या इसे बिखर जाने दो। कुछ हिंदू राष्ट्र-विरोधी तत्वों से हाथ मिला चुके हैं जो हिंदुओं को खण्ड-खण्ड करने के लिए सक्रिय हैं। शहरी हिंदू यह अनुभव करने लगे हैं कि यदि उन्हें जीवित रहना है, तो उन्हें हिंदुओं को संगठित करना पड़ेगा। यही उनके सामने विकल्प है। यह अस्तित्व का सवाल है।

माया: क्या आपका आशय यह है कि 'भय' इन सब बातों के मूल में है? क्या औसत हिंदू अपने भविष्य के प्रति भयभीत है?

सिंघल: हां, हिंदू धर्म का भविष्य अंधकारमय है। अब हिंदू अनुभव करते हैं कि वे बंट चुके हैं। भारत को छोड़कर इस्लाम मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है और भारत ४५ इस्लामिक देशों के बीच पिस रहा है। और जब वे कहते हैं, 'हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान' और जिस तरह से इस देश में वह भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हर हिंदू अब यह पूछने लगा है कि क्या अपने ही देश में वे अपने अस्तित्व को कायम रख पायेंगे।

माया: क्या चुनावी लाभ के लिए धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण हो गया है?

सिंघल: यकीनन, अभी तक तो कांग्रेस ही मुस्लिम समर्थन पाने के लिए धार्मिक मामलों को उछालती रही है। इस पार्टी ने धर्म को एक हथकण्डे के रूप में इस्तेमाल किया और हिंदू संगठनों के प्रति घृणा फैलाने का अभियान चलाया। इस सबसे कांग्रेस को ही वास्तव में लाभ पहुंचा। अब मुसलमानों ने भी ऐसा ढर्रा अपना लिया है। वे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और राज्यों में विपक्ष का। इस प्रकार मुसलमान इस देश में सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों का समर्थन कर रहे हैं।

माया: क्या यह विडंबना नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी बहुसंख्यक समुदाय के बजाय अल्पसंख्यकों का समर्थन चाहती है?

देश में सशस्त्र विद्रोह कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, जिनकी योजना विदेशी जमीन पर बनती है। इस षड्यंत्र की जड़ें भारत में नहीं, विदेश में हैं और कोशिश हिंदू समाज को तोड़ने की है। वे भारतीयों को ही हिंदुओं से लड़ने के लिए हथियारबंद करना चाहते हैं।

सिंघल : हां, यही विडंबना है। यहां मुसलमानों को 'मुस्लिम वोट बैंक' कहा जाता है, लेकिन 'हिंदू वोट बैंक' जैसी किसी बात का अस्तित्व नहीं है।

माया : क्या 'हिंदू वोट बैंक' का निर्माण करने की कोई कोशिश हो रही है ? क्या यह कोशिश 'मुस्लिम वोट बैंक' की प्रतिक्रिया है ?

सिंघल : अब जबकि हिंदू स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनकी यह धारणा बनती जा रही है कि यदि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाना है, तो उन्हें सिर्फ उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो दिल से उनका हित चाहती हो। और मैं कह सकता हूं कि केरल के विधानसभा चुनावों में यह दृश्य दिखाई दिया था। कांग्रेस-इ तब ईसाई और मुस्लिम लीग के वोटों का भरोसा किये हुए थी, लेकिन हिंदुओं के वोट न मिलने के कारण वह सत्ता हासिल नहीं कर सकी। हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिया जो ईसाइयों और मुसलमानों को तुष्ट करने में लगे थे और यही वजह थी कि कांग्रेस-इ वहां हार गयी। पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमान केरल मंत्रिमंडल में कोई स्थान प्राप्त करने में असफल रहे।

माया : क्या राजनीति और धर्म के बीच कोई सीमा-रेखा निर्धारित नहीं होनी चाहिए ?

सिंघल : यकीनन। हिंदू महज एक धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में सैकड़ों संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह हमारी मान्यता रही है और हम इस पक्ष के हैं कि धार्मिक संप्रदायों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सिख धर्म हिंदुओं का एक धार्मिक संप्रदाय है, जैसे लिंगायत और जैन। लेकिन लिंगायत और जैन धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ते, तो फिर अन्य संप्रदायों को ऐसा क्यों करना चाहिए ?

माया : इन दिनों हम देखते हैं कि धार्मिक संप्रदाय राजनीति पर हावी होते जा रहे हैं जैसे सिख पंजाब की राजनीति के नियंता बन गये हैं ?

सिंघल : हम पंजाब में इसका परिणाम भी देख रहे हैं। वहां दो धार्मिक गुट हैं, जिन्होंने वहां राजनीतिक दल बना लिये हैं और उन्हीं आधारों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी भी दो धड़ों में बंट गयी है। हम समझते हैं कि स्वस्थ राजनीति के लिए धार्मिक संप्रदायों को राजनीतिक पार्टियां नहीं बनानी चाहिए।

माया : हिंदुओं की इस जागरूकता का अंततोगत्वा परिणाम क्या होगा ? आबादी का ८० प्रतिशत होने के कारण बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यकों से डरने की आवश्यकता क्यों है ?

सिंघल : मेरे दिमाग में खाका कुछ भिन्न है, क्योंकि जिसे आप धर्म कहते हैं, मैं समझता हूं, वह संप्रदाय है। अतः जब आप धर्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब है, सभी धार्मिक संप्रदाय। यकीनन इसे आप हिंदू धर्म का जागरण कह सकते हैं। वास्तविकता यह है कि आज हिंदुओं के धार्मिक नेता जितने जागृत हैं, उतने पहले कभी नहीं रहे। हमने सुना है कि जयेंद्र सरस्वती ने अपने मठ और पारंपरिक पूजा का परित्याग कर दिया है। यह सब उन्होंने केवल हिंदू समाज की सेवा के लिए किया है। मैं समझता हूं कि न केवल जयेंद्र सरस्वती, बल्कि सभी धार्मिक नेता संकट की घड़ी में हिंदू समाज की सेवा के लिए आगे आयेंगे। इस समय हमारे सामने प्रमुख रूप से दो खतरे हैं। उत्तर में राष्ट्र विरोधी तत्व विदेशी धन की मदद से सिखों को भड़काकर देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण में तमिलों को विदेशी शक्तियों द्वारा हथियार दिये गये हैं। आप जानते हैं, जाफना से कितनी भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। सवाल यह है कि यदि विदेशी ताकतों की हमारे घरेलू मामलों में रुचि नहीं है, तो फिर किसने सिखों और तमिलों को ये हथियार दिये। इनके पास इतना धन नहीं है कि वे इतने हथियार खरीद सकें। हम जानते हैं कि नागालैण्ड के ईसाई विद्रोहियों को भी इसी तरह हथियार प्राप्त हुए हैं। अतः देश में सशस्त्र विद्रोह कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, जिनकी योजना विदेशी जमीन पर बनती है। इस षड्यंत्र की जड़ें भारत में नहीं, विदेश में हैं और कोशिश हिंदू समाज को तोड़ने की है। वे भारतीयों को ही हिंदुओं से लड़ने के लिए हथियारबंद करना चाहते हैं। संक्षेप में विदेशी ताकतों का यही षड्यंत्र है, जिसे हमें नाकाम करना है।

> यदि वहां सरकार मस्जिद बनाने की अनुमति देती है, तो निश्चितरूप से हिंदू यह सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इस मुद्दे पर तो जनता पार्टी और लोकदल तक में दरार पड़ जायेगी और वही वर्ग अस्तित्वमान रहेगा और संसद में पहुंचेगा जो हिंदू-हितों का समर्थक होगा। मुसलमान राजनीतिक रूप से चुकी हुई ताकत भर रह जायेंगे।

माया : क्या आप इस्रायल सरीखे हिंदू राज्य की वकालत करते हैं ?

सिंघल : राणा रणजीत सिंह और शिवाजी के शासन के दौरान भारत को हिंदू राज्य कहा जा सकता था। हिंदू हमेशा से उदार रहे हैं, इसलिए इन अर्थों में राज्य के संबंध में हिंदू-मान्यता और इस्लामिक मान्यता के बीच बहुत भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर किसी अरब मुल्क में आप मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन भारत में आप मस्जिद या चर्च का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यदि मुसलमान राम जन्म भूमि या काशी विश्वनाथ में मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। हिंदू उदारता का मतलब है कि पारसी और तिब्बत के बौद्ध लामा जैसे बाहर से आने वाले संप्रदायों को भारत में अपने-अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन यदि ये धार्मिक संप्रदाय ऐसा सोचते हैं कि वे हिंदू समाज को धर्मांतरित कर देंगे, तो हम इसे सहन नहीं करेंगे।

माया : क्या आप समझते हैं कि हिंदू 'हिंदू राज्य' स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं ?

सिंघल : मैं समझता हूं कि हिंदू जागरूकता अंततः स्वयमेव हिंदुओं को शीर्ष स्थान पर ले जायेगी और विभिन्न राजनीतिक दलों को अंततोगत्वा हिंदू हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। जो राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा, उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा।

माया : क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना अव्यावहारिक नहीं है ? क्या इसमें देश के टुकड़े हो जाने का खतरा अन्तर्निहित नहीं है ?

सिंघल : नेपाल हिंदू राष्ट्र है ? यदि नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है, तो क्या वहां कोई भारी विस्फोट हो जायेगा ? या मुसलमानों में बेचैनी बढ़ जायेगी ? मैं समझता हूं, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा।

माया : क्या आपका आशय यह है कि 'हिंदू राष्ट्र' की इस मान्यता से देश के टूटने या रक्तपात होने का खतरा नहीं है ?

सिंघल : निश्चित रूप से। असलियत यह है कि 'हिंदू धर्म क्या है ?'— इसे समझाया ही नहीं गया। अलीगढ़ मुस्लिम

किसी अरब मुल्क में आप मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन भारत में आप मस्जिद या चर्च का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यदि मुसलमान राम जन्म भूमि या काशी विश्वनाथ में मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो हम इसे सहन नहीं करेंगे।

विश्वविद्यालय के संस्थापक ने लाहौर और गुरदासपुर में दी गयी अपनी तकरीरों में कहा था, "इस देश के सारे मुसलमान मूलतः हिंदू ही हैं। ऐसे ही ईसाई भी हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं प्रबुद्ध ईसाई डा० वी०वी० जोन ने कहा था कि धार्मिक दृष्टि से हम ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हम सभी की कौम हिंदू है।

माया: धर्मांधता और रूढ़िवाद ने ईरान और पंजाब में खून बहाया है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या हिंदुओं में बढ़ती जागरूकता देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न नहीं कर देगी?

सिंघल: नहीं। हिंदू अन्ततः मुसलमानों का राजनीतिक तुष्टीकरण करना बंद कर देंगे। हिंदू इस तुष्टीकरण के खिलाफ वोट देंगे जैसा कि उन्होंने केरल में किया। एक राजनीतिक ताकत के रूप में मुसलमानों को अलग-थलग कर दिया जायेगा। इससे कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। इससे मुसलमानों में नया सोच जन्म लेगा और उनके नेतृत्व में पूरी तरह से परिवर्तन हो जायेगा।

माया: क्या हिंदू समुदाय के नेता हिंदुओं को और प्रतिक्रियावादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

सिंघल: नहीं। आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं कि हिंदू अधिकाधिक प्रतिक्रियावादी होते जा रहे हैं?

माया: क्या उन्हें भड़काया नहीं जा रहा? क्या उनसे यह नहीं कहा जा रहा कि वे और जागरूक हिंदू बनें?

सिंघल: हिंदुओं को अपना घर ठीकठाक करने के लिए स्वयं संगठित होना है। छुआछूत, दहेज और सती प्रथा का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। ये बुराइयां समाज द्वारा दूर होंगी न कि राजीव गांधी जैसे राजनेताओं द्वारा। क्योंकि इससे सुधार संभव नहीं, बल्कि ये राजनेता इन बुराइयों को राजनीति का रंग दे देते हैं?

माया: जब आप हिंदुओं को संगठित करने की बात करते हैं, तब आप हिंदू संगठनों को सांप्रदायिकता का लेबल लगने से कैसे बचा पायेंगे। आप सांप्रदायिकता से ग्रस्त जमायते इस्लामी, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे ही अन्य संगठनों के बीच कैसे अंतर करेंगे?

सिंघल: सांप्रदायिकता को कभी परिभाषित नहीं किया गया। यह दो संप्रदायों के बीच संभव है, लेकिन जब सैकड़ों धार्मिक संप्रदाय ही मिलकर हिंदू धर्म का निर्माण करते हैं, तो हिंदू धर्म कैसे सांप्रदायिक हो सकता है? यह इस्लाम से भिन्न है। उनके पास एक पैगंबर है और एक पवित्र किताब। यदि आप कट्टरता से उनका पालन करते हैं और समय के साथ नहीं बदलते, तो आप रूढिवादी होंगे। हिंदुओं में न ऐसी कोई किताब है और न ही मसीहा। अतः हिंदुओं में रूढ़िवाद को स्थान मिलना संभव ही नहीं है।

मैं समझता हूं कि हिंदू जागरूकता अंततः स्वयमेव हिंदुओं को शीर्ष स्थान पर ले जायेगी और विभिन्न राजनीतिक दलों को अंततोगत्वा हिंदू हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। जो राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा, उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा।

माया: हिंदू समाज का भविष्य क्या होगा? हिंदुओं में बढ़ती नाराजगी का परिणाम-क्या होगा और उनकी यह नाराजगी कैसे दूर होगी?

सिंघल: ऐसा लगता है कि हिंदू समाज भारत विरोधी विदेशी शक्तियों का निशाना बन गया है और दुर्भाग्य से हमारे राजनेता इन विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। दक्षिण भारत में हमारे मंदिरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वह मस्जिदों और गिरजाघरों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हिंदू अपने मंदिरों पर सरकार का कब्जा क्यों होने देंगे। मैं समझता हूं कि इन सब बातों के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन जन्म लेगा जो पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देगा। उदाहरण के रूप में राम जन्म भूमि विवाद को लें। यदि वहां सरकार मस्जिद बनाने की अनुमति देती है, तो निश्चित रूप से हिंदू यह सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इस मुद्दे पर तो जनता पार्टी और लोकदल तक में दरार पड़ जायेगी और वही वर्ग अस्तित्वमान रहेगा और संसद में पहुंचेगा जो हिंदू-हितों के समर्थक होंगे। मुसलमान राजनीतिक रूप से चुकी हुई ताकत भर रह जायेंगे।

माया: क्या ऐसा आंदोलन हमें समय से पीछे नहीं ले जायेगा?

सिंघल: हिंदू धर्म संकुचित और बंद समाज नहीं है, अतः ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। यह निरंतर परिवर्धित होने वाला समाज है। यहां तक कि समय की आवश्यकतानुसार वेदों के भाष्य भी बदलते रहे हैं। हिंदू समाज खुला और गतिशील समाज है। यह परिवर्तन व परिवर्धन की अनुमति देता है। अतः यह सवाल ही नहीं उठता कि यह रूढिवादी बनकर रह जायेगा।

माया: क्या आप कहना चाहेंगे कि हिंदू केवल अपने अधिकारों के लिए नाराज हैं?

सिंघल: हां, और वास्तविकता में ऐसा है भी। बहुसंख्यकों के संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि अल्पसंख्यकों के संस्थान आजाद हैं। क्या यह संवैधानिक है? या तो सभी संस्थान सरकारी नियंत्रण में हों या फिर कोई न हो। आज हर कोई अपने को अल्पसंख्यक कहलाना चाहता है। हर मिशन अपने को अल्पसंख्यकों का मिशन घोषित करता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ विसंगतियां हैं। गौ हत्या का उदाहरण लें। इस देश में कोई नहीं चाहता कि गोवध हो। यह बात हमारे संविधान में प्रतिबंधित होनी चाहिए। इस संबंध में मुसलमानों के विरोध की चिंता क्यों? लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। हिंदू धर्म के खिलाफ इस भेदभाव का अंत करने के लिए महा जनजागरण होगा, जिससे कोई राजनीतिक पार्टी फिर अछूती नहीं रह पायेगी और २१वीं सदी का हिंदू नये रूप में उभरेगा जो अपराजेय होगा। ■

सत्यकथा

दिसम्बर १९८७
मूल्य रु० ५/-

राजकुमारी ज्योत्सना की प्रेमगाथा

राजकुमारी ज्योत्सना और कुंवर शेरसिंह के युवा दिलों में उपजे प्रेम संबधों को जागीरदारी की झूठी मान-मर्यादा द्वारा ढहा दिये जाने की कथा.

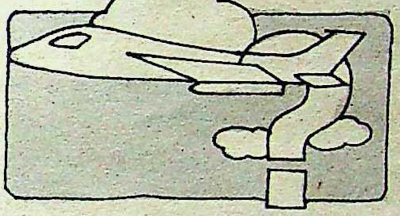

आकाश की बेटी कहां गयी ?

महिला पायलट एमलिया अरहार्ट के विश्वयात्रा के दौरान विमान सहित लापता हो जाने की कथा.

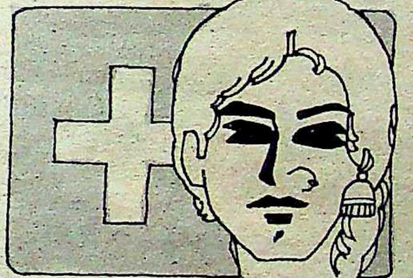

यास्मीन खातून से मोहम्मद यासीन

लखनऊ में २० वर्षीया एक युवती के यौन परिवर्तन द्वारा युवक बन जाने की आत्मकथा.

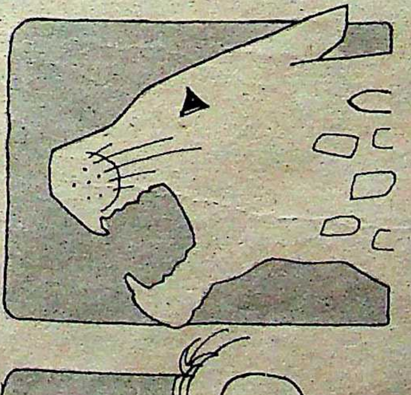

मौत के मुंह से लौटा नागेश्वर

एक चीते के साथ पांच घंटे एक कोठरी में बंद ५ वर्षीय बालक को सकुशल कोठरी से निकाले जाने की कथा.

बेटी की इज्जत का सवाल

एक विवाहित द्वारा शरीफ खानदान की लड़की को बदनाम करने का कुपरिणाम सामने आने की कथा

अन्य आकर्षण

अधूरा लगन

आगरा में पतियों को कपड़े की तरह बदलने वाली एक युवती द्वारा अपनी एक सहेली के भाई की हत्या कर दिए जाने की कथा.

अपरिचित को नौकर रखने का परिणाम

बम्बई में पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद अपरिचित को नौकर रखने के कुपरिणाम की कथा.

कमरूदीन की वापसी

कानपुर में नौकरी से हटा दिए गए एक नौकर द्वारा भू०पू० मालिक के पुत्र के अपहरण की कथा.

हम रह गये अकेले

मोहब्बत का जुनून

सूर्यबाला की प्रेम कथा

साथ ही
सनसनी खेज सम्पूर्ण
चित्र कथा.

एक अविस्मरणीय पारी

यह गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी के ही बस की बात है, जिसने टेस्ट मैच के अनुसार ढले अपने खेल को समय के साथ एक दिवसीय मैचों के अनुरूप बना दिया। रिलायंस कप में ३१ अक्तूबर को विदर्भ क्रिकेट संघ मैदान पर धमाकेदार शतक जड़ कर उन्होंने उन आलोचकों के मुंह बंद कर दिये, जो उन्हें एक दिवसीय मैचों के लायक मानने को तैयार नहीं थे। विश्वकप मैचों में दूसरा सबसे तेज शतक बनाकर उन्होंने दिखला दिया कि जरूरत पड़ने पर वे चौकों-छक्कों वाली पारी भी खेल सकते हैं। उस दिन नागपुर में गावस्कर का धुंआधार प्रदर्शन न सिर्फ नयी पीढ़ी के लिए अपने आप में एक पाठ था, बल्कि देश में प्रसन्नता व गौरव की लहर का सूत्रपात भी था। गावस्कर उस दिन भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक बन गये थे (१०३ रन, तीन छक्के और दस चौके)।

विख्यात कमेंटेटर **रवि चतुर्वेदी** उस दिन नागपुर से दूरदर्शन पर इस मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। प्रस्तुत है, गावस्कर की उस महान पारी को देखने का अनुभव उन्हीं की कलम से:

गावस्कर एक दृढ़ संकल्प खिलाड़ी हैं और वह जो सोच लेते हैं, अवश्य कर दिखाते हैं। इस संदर्भ में मुझे याद आता है सन १९८३ की भारत-वेस्टइंडीज श्रृंखला का कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच। वेस्टइंडीज ने कानपुर के पहले टेस्ट मैच में भारत को एक पारी और ८१ रनों से पराजित कर दिया था। भारत की पराजय का मुख्य कारण था गावस्कर की असफलता। उससे भी कहीं अधिक उल्लेखनीय घटना थी दूसरी पारी में मार्शल की एक शार्ट पिच गेंद से गावस्कर के हाथ से बल्ला छूटकर दूर जा गिरना और बल्ले से उछला हुआ कैच लपक लिया जाना। मुझे ऐसा लगा कि गावस्कर ने नहीं, बल्कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की रफ्तार के सामने घुटने टेक दिये हों। वह एक बहुत बड़ी चुनौती थी।

भारतीय बल्लेबाजी का मनोबल बहुत गिर चुका था। लग रहा था, क्लाइव लायड की वेस्टइंडीज टीम विश्वकप में अपनी पराजय का बदला जम कर चुकायेगी। इसके बाद आया फीरोजशाह कोटला नयी दिल्ली में वेस्टइंडीज के ही विरुद्ध दूसरा टेस्ट मैच, जिसमें गावस्कर ने तूफानी मार्शल, होल्डिंग, डेविस और डेनियल को आड़े हाथों लिया और सौ गेंदों के पहले ही अपना शतक अर्जित कर लिया।

यह शतक अपने आप में जहां गावस्कर के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि और कीर्तिमान था, वहीं यह भारतीय बल्लेबाजों को तूफानी गेंदबाजी के विरुद्ध आत्मविश्वास दिलाने में भी सहायक रहा। इस शतकीय पारी में उन्होंने भारतीय टीम का मार्गदर्शन किया और बताया कि वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाजों का सामना कैसे किया जा सकता है। इस प्रेरणा का परिणाम यह निकला कि इसी टेस्ट मैच में दिलीप वेंगसरकर ने भी शतक ठोक दिया।

१९८७ विश्वकप में जिम्बाब्वे के विरुद्ध दूसरे मैच में भारतीय पारी बहुत धीमी गति से आरंभ हुई जिससे भारत के रन बनाने की औसत काफी कम हो गयी। अपने पूल के अंतिम मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत को तेजी से रन बनाना और विजय प्राप्त करना भी अनिवार्य हो गया था, ताकि वे अपने वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकें। एक बार फिर भारतीय बल्लबाजों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गयी थी। अपने इन दोनों उद्देश्यों में भारत यदि सफल रहा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका सुनील मनोहर गावस्कर की रही।

गावस्कर यदि यह शतक किसी अन्य एक दिवसीय मैच में बनाते, तो इतनी चर्चा नहीं होती, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा एक दिवसीय मैच खेले जा रहे हैं कि लोग उन्हें याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन विश्वकप प्रतियोगिता, एक दिवसीय क्रिकेट में एक अलग महत्व रखती है। उसके अपने अनोखे रिकार्ड हैं। इसलिए सुनील गावस्कर ने जो शतक बनाया वह उनका अविस्मरणीय शतक था। मैच की

गावस्कर की यह पारी बरसों याद की जायेगी : सुनील गावस्कर

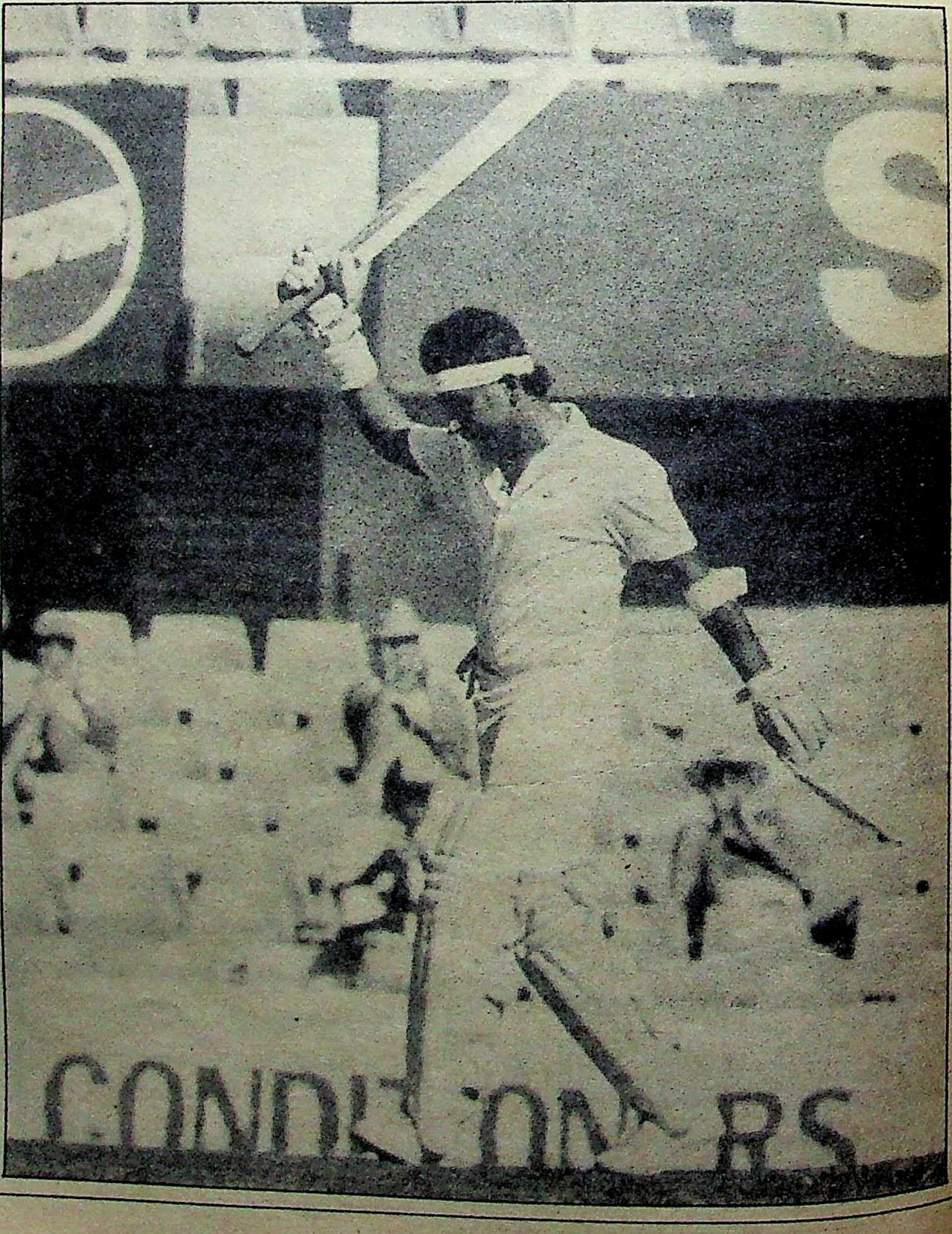

पूर्व संध्या पर गावस्कर ज्वरग्रस्त थे। इस कारण शारीरिक और मानसिक रूप से वह सशक्त न थे। इसलिए भी चौथे विश्वकप में गावस्कर का यह पहला शतक चिरस्मरणीय रहेगा।

विश्वकप में इससे पहले गावस्कर का सर्वाधिक स्कोर ६५ रन (अविजित) था, जो उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के विरुद्ध लीड्स में पहले विश्वकप में १९७५ में बनाया था। इस शतक के साथ गावस्कर ने एक दिवसीय क्रिकेट में तीन हजार से ज्यादा रन बना लिये हैं। उन्होंने १०६ मैच खेले हैं और ३०८८ रन बनाये हैं, जो कि भारत की ओर से एक बैट्समैन द्वारा बनाये गये सर्वाधिक रन हैं।

नागपुर में गावस्कर ने अपना शतक ८५ गेंदों में पूरा किया था। पहले विश्वकप फाइनल में लार्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर १९७५ में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध लायड ने ८२ गेंदों में धुंआधार शतक बनाकर वेस्टइंडीज को विजय दिलायी थी। गावस्कर के धुंआधार शतक ने १९७५ की यादों को फिर से ताजा कर दिया। इस मैच में एक और भारतीय कीर्तिमान स्थापित हुआ, जब गावस्कर ने श्रीकांत के साथ पहले विकेट की साझेदारी में १३६ रन बनाये। पहले विश्वकप में पहले विकेट के लिए इंजीनियर और गावस्कर ने पूर्वी अफ्रीका के विरुद्ध लीड्स में १२३ रन बनाये थे।

पहले नौ ओवर में गावस्कर और श्रीकांत ने ७० रन अर्जित करके सिद्ध कर दिया कि भारत यह मैच आसानी से जीतेगा। जिस तेजी से और धुंआधार तरीके से गावस्कर और श्रीकांत खेल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे नुमाइशी क्रिकेट खेली जा रही हो। क्लाइव लायड ने अपने स्तंभ में साफ लिखा है, "उस दिन ऐसा लग रहा था कि कार्नीवल क्रिकेट हो रहा हो।"

३१ अक्तूबर भारतीय क्रिकेट में एक और स्मृतिदायक दिवस है। ठीक ९२ वर्ष पूर्व इसी दिन (३१ अक्तूबर) को भारतीय क्रिकेट के पितामह स्व० सी०के० नायडू का जन्म इसी शहर (नागपुर) में हुआ था। गावस्कर भी स्व० नायडू की शैली में खेल रहे थे, मगर उनका खेल देखने के लिए वह वहां मौजूद न थे। लेकिन उनके सबसे प्रिय शिष्य मुश्ताक अली उस मैदान पर मौजूद थे। गावस्कर की धुंआधार पारी को देखकर वह भावविभोर हो गये होंगे। यह वही शैली थी जिसके जन्मदाता स्व० नायडू थे और जिसका अनुकरण स्वयं मुश्ताक अली ने अपने जमाने में किया था। यह भी संयोग ही कहा जायेगा कि चेटफील्ड की गेंद पर लगा एक छक्का मुश्ताक अली के चरणों में आकर गिरा। ऐसा लगा मानो गावस्कर मुश्ताक साहब का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हों।

श्रीकांत अधिक आक्रामक बल्लेबाज समझे जाते हैं, लेकिन गावस्कर के बल्ले से रन अनायास ही निकल रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह कोई प्रयास कर रहे हैं रन बनाने के लिए। भारत के १०० रन केवल ८० गेंदों पर बने।

इस मैच में पारी की शुरुआत में गावस्कर ने श्रीकांत से पूछा था कि क्या हम दोनों यह मैच २५ ओवर में समाप्त कर सकते हैं? श्रीकांत ने अपनी सहमति व्यक्त की थी। गावस्कर का यह प्रश्न इस बात का परिचायक है कि उन्होंने यह संकल्प कर रखा था कि आज भारत को अच्छी रन रफ्तार प्रदान करेंगे और न्यूजीलैंड को भलीभांति पराजित करेंगे।

मुझे याद आता है सन १९७६ की भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट श्रृंखला जिसमें ब्रजटाउन बारबेडास में खेले गये पहले मैच में भारत को पारी की हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद विजयी कप्तान क्लाइव लायड ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह कहा कि वह श्रृंखला आसानी से जीत जायेंगे। उनसे जब और स्पष्ट करने को कहा गया, तो लायड ने कहा भारत ढाई बल्लेबाजों की टीम है। यानी गावस्कर और विश्वनाथ को एक-एक बल्लेबाज आंका जाता था और शेष टीम को आधा बल्लेबाज। लेकिन क्रिकेट महान खेल है। आज जो राजा है, कल वह रंक बन जाता है। तीसरे टेस्ट मैच में इसी ढाई बल्लेबाज की टीम ने ४०६ रन बनाकर लायड को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। उसमें गावस्कर की शतकीय भूमिका रही थी। वह शतक भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

SAFI
साफ़ी
SAFI

मोहक त्वचा! साफ़ी त्वचा!

कील-मुहासे, फोड़े-फुंसियां तथा त्वचा के अन्य रोग रक्त में विकार के चिन्ह हैं। रक्त के विकार से स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में आपको साफ़ी के स्वास्थ्यदायक तत्वों की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

साइन्टिफ़िक रिसर्च ने भी सिद्ध कर दिया है कि साफ़ी एक हानि-रहित रक्तशोधक औषधि और कीटाणु-नाशक है, और यह त्वचा को साफ़ और सुन्दर बनाती है तथा अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है।

निःसंदेह, साफ़ी पचास वर्षों से अधिक समय से एक सुप्रसिद्ध रक्तशोधक औषधि है।

२४ अत्यावश्यक रक्तशोधक तत्वों और जड़ी-बूटियों का अनोखा मिश्रण

हमदर्द

साफ़ी

रक्त को साफ़ करती है। त्वचा को निखारती है।

HTA-5048BH

Over 1,40,000 homes are now looking through the inner eye!

ALOKPAAT

The real-life, human interest Bengali monthly that's achieved a record-breaking 1,40,000 copies in just 6 months!

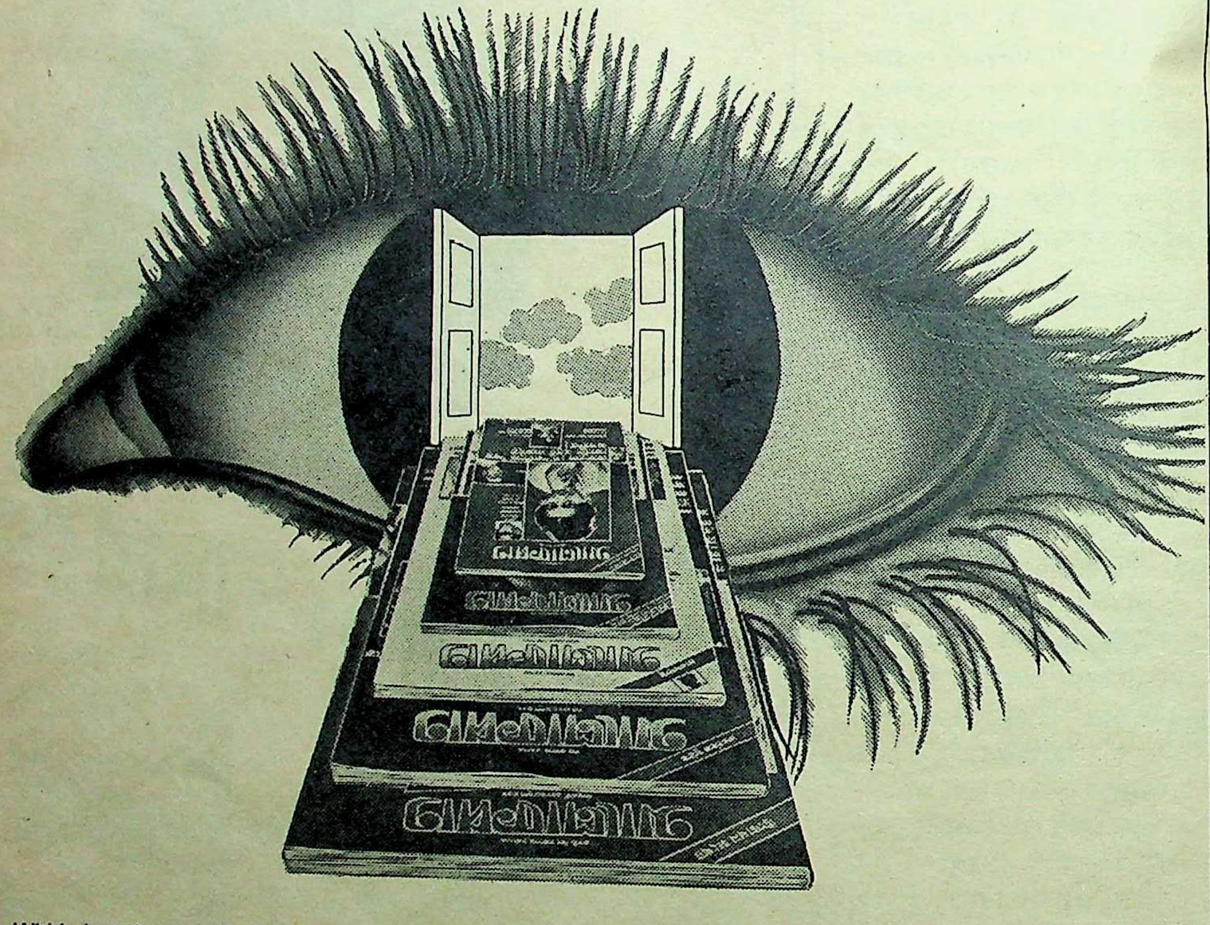

Within just six months of its launch, Alokpaat has reached into over 1.40 lakh homes—opening up an exciting new dimension in journalism. As the first investigative Bengali monthly to offer a unique insight into the real-life dramas that are intriguing the world every day—Alokpaat has captured the imagination and enthusiasm of thousands of men and women. It is this *enthusiasm that has made Alokpaat a runaway success —with each new issue* virtually 'sold-out' as soon as it hits the stands.

The Alokpaat growth curve—a unique picture of success

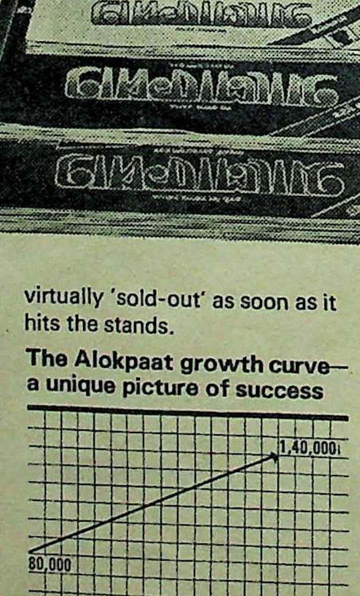

আলোকপাত

ALOKPAAT

A unique milestone in Bengali journalism

—now a unique best-seller

MITRA PRAKASHAN
PRIVATE LIMITED
Allahabad

SAA/MP/13

श्रीमती सरोज वर्मा

चरण सिंह की बेटी ने आत्महत्या क्यों की ?

चौधरी चरण सिंह की पुत्री सरोज वर्मा ने यद्यपि अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय माना जाता था। पति गन्ना उप आयुक्त के पद से 'सेवा निवृत्त' होकर राजनीति में उनके सहयोगी थे। राजनीति में अपने जुझारूपन के लिए वह विख्यात हो रही थीं। फिर वे कौन से कारण थे, जिन्होंने लोकदल-अ की प्रादेशिक महामंत्री और विधायक श्रीमती सरोज वर्मा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया ? :

रहस्यमय आत्महत्या : स्व० सरोज वर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा देते पति अविनाश चन्द्र वर्मा और भाई अजीत

भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुत्री तथा लोकदल (अ) की विधायक श्रीमती सरोज वर्मा ने लखनऊ के राजभवन कालोनी स्थित अपने आवास पर गत २५ अक्तूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से राजनीतिक क्षेत्रों में तहलका मच गया। लोगों को यकायक यह विश्वास नहीं हुआ कि राजनीति में अपने जुझारूपन के लिए मशहूर सरोज वर्मा ने खुदकशी कर ली है।

चौधरी चरण सिंह की बीमारी के बाद सरोज वर्मा ने जिस तेजी से प्रदेश की राजनीति में अपने कदम बढ़ाये थें, उससे लोकदल के प्रादेशिक नेताओं में हडकम्प मच गया था। यही कारण था कि चौधरी साहब की मृत्यु के बाद सरोज वर्मा का अच्छा-खासा रुतबा हो गया था।

पचास वर्षीया श्रीमती सरोज वर्मा लोकदल (अ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह की सगी बहन थीं। वह इन दिनों पार्टी की प्रादेशिक महामंत्री भी थीं। उनके पति अविनाश चन्द्र वर्मा उप आयुक्त (गन्ना) के पद से कुछ दिनों पूर्व ही अवकाश मुक्त हुए थे। श्री वर्मा इन दिनों अपनी पत्नी के साथ राजनीतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग लेते रहे थे। वे दोनों राजभवन कालोनी के २६ बी० नम्बर सरकारी आवास में रहते थे। श्रीमती वर्मा महत्वाकांक्षी महिला थीं।, उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हैं। बड़ा लड़का सुधीर वर्मा तेजपुर में फ्लाइट लेफ्टीनेंट के पद पर कार्यरत है तथा अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता है। उससे छोटा, प्रियदर्शी दिल्ली में रहकर कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पुत्री संध्या का विवाह दिल्ली में हुआ है।

श्रीमती वर्मा के लखनऊ स्थित आवास पर उनके पति अविनाश वर्मा के अतिरिक्त एक नौकर बद्री रहता था। दीपावली के अवसर पर श्री वर्मा के छोटे भाई नवीनचन्द्र वर्मा, सपरिवार उनके यहां आये थे। दीपावली की छुट्टी पर छोटा पुत्र प्रियदर्शी भी माता-पिता के पास आया हुआ था।

घटनाक्रम : घटनावाले दिन शाम लगभग सवा चार बजे युवा लोकदल (अ) के पांच कार्यकर्ता श्रीमती वर्मा के आवास पर पहुंचे। घर पर उस समय श्रीमती वर्मा के अतिरिक्त उनके पति, देवर नवीन, देवरानी, भतीजी, पुत्री आदि थे। 'ड्राइंगरूम' में श्रीमती वर्मा तथा कार्यकर्ताओं के मध्य लगभग एक घंटे तक बातचीत होती रही। श्रीमती वर्मा ने उन कार्यकर्ताओं को मिठाई आदि खिलाई। इस बातचीत के दौरान श्रीमती वर्मा के परिवार के सभी सदस्य दूसरे कमरे में थे।

सवा पांच बजे के आस-पास श्रीमती वर्मा ने कार्यकर्ताओं को विदा करते हुए कहा, "अच्छा, अब आप लोग जाइये। मैं क़ाफी थकी हूं, आराम करूंगी।"

कार्यकर्ताओं के जाने के बाद श्रीमती वर्मा सीधे बाथरूम में चली गयीं। बाथरूम का एक अन्य दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता था। उस रात श्रीमती वर्मा के देवर नवीनचन्द्र को परिवार सहित वापस वाराणसी जाना था। उनका काशी विश्वनाथ ट्रेन से 'रिजर्वेशन' था। उस समय श्रीमती वर्मा की देवरानी अपना सामान बांधनें में व्यस्त थीं। बाथरूम में जाने के कोई दो मिनट बाद ही श्रीमती वर्मा बाहर आयीं और देवरानी से बोलीं, "मुझे १२ नवम्बर को बलिया जाना है। तुम वाराणसी स्टेशन पर मुझसे मिल लेना। उस दिन मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी।" देवरानी ने क्या जवाब दिया, यह तो पता नहीं चल सका, लेकिन उसी के बाद श्रीमती वर्मा बाथरूम में चली गयीं। जिस समय श्रीमती वर्मा देवरानी से बात करने बाहर आयी थीं वह केवल साड़ी और ब्लाउज पहनें थीं। ब्लाउज के नीचे के दो बटन खुले हुए थे। इससे ऐसा लग रहा था कि वह नहाने जा रही थीं, तभी वाराणसी स्टेशन पर देवरानी के मिलने की बात याद आते ही, वह बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गयी थीं।

देवरानी से बात करने के बाद जब श्रीमती वर्मा बाथरूम में गयीं, तो फिर जिंदा नहीं लौटीं। लगभग पौन घंटे तक जब श्रीमती वर्मा बाथरूम से नहाकर नहीं निकलीं, तो देवरानी को कुछ संदेह हुआ। उसने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगायी, "दीदी, दीदी"। लेकिन अन्दर से कोई आवाज नहीं आयी।

सशंकित तथा परेशान परिवारजन बाथरूम

के दूसरे द्वार की ओर भागे कि शायद वह खुला हो। परन्तु बाथरूम के साथ सटा हुआ कमरा भी अन्दर से बंद था। काफी धक्के देने के बाद कमरे के दरवाजे की कुंडी अन्दर से टूट गयी। कमरे का दृश्य देखते ही सभी के होश उड़ गये। अन्दर श्रीमती वर्मा फंदे पर झूल रही थीं। आनन-फानन में उन्हें नीचे उतारा गया, परन्तु तब तक श्रीमती वर्मा इस दुनिया से काफी दूर जा चुकी थीं। पूरे घर में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे। अभी मौका-मुआयना चल ही रहा था कि मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी खबर मिलते ही वहां आ गये।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने प्रदेश के जाने-माने चिकित्सा विधि विशेषज्ञ डा० के०के० सिंघल को भी बुलवा लिया। हस्तलिपि विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंच गये। सी०आई०डी० अधिकारी भी वहां आ गये। घटना के सभी पहलुओं पर छानबीन की जाने लगी। काफी खोजबीन के बावजूद घटनास्थल से ऐसा कोई पत्र आदि बरामद नहीं हुआ, जिससे श्रीमती वर्मा द्वारा आत्महत्या करने की पुष्टि होती। पुलिस को कमरे से चालू वर्ष की कोई ऐसी डायरी भी नहीं मिली, जिसमें श्रीमती वर्मा द्वारा दिनचर्या लिखी जाती हो। जबकि पिछले वर्षों की डायरियां उनके कमरे में मौजूद थीं। श्रीमती वर्मा का शव भी परिवारवालों ने फंदे से निकाल लिया था, जिससे वास्तविक स्थिति का आकलन करने में पुलिस को कठिनाई महसूस हो रही थी।

बहरहाल, काफी देर तक जांच-पड़ताल करने के बाद पुलिस को आत्महत्या का ही पहलू सबसे ज्यादा मजबूत लगा, क्योंकि ऐसा कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था, जिससे अन्य सभावनाओं के बारे में शक भी किया जाता।

पुलिस का मत: पुलिस के अनुसार श्रीमती वर्मा ने पंखे में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। घटना से पूर्व श्रीमती वर्मा जो साड़ी पहने थीं उसी को रस्सी की तरह बटकर फंदा बनाया गया था। मृत्यु के समय वह केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थीं। जिस कमरे में श्रीमती वर्मा ने आत्महत्या की थी, उसमें दो चारपाइयां पड़ी थीं। पास ही लोहे की एक 'फोल्डिंग टेबुल' उल्टी गिरी पड़ी थी। पुलिस का अनुमान था कि श्रीमती वर्मा ने चारपाई पर टेबुल रखकर फंदा बनाया होगा और उस पर लटकने के बाद पैर से टेबुल गिरा दी होगी।

मुख्यमंत्री के आदेश पर श्रीमती वर्मा का पोस्टमार्टम उसी दिन आधी रात के समय ए०के० सक्सेना द्वारा किया गया। डा० सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मामला पूरी तरह आत्महत्या का है। उन्होंने मृत्यु का कारण, फांसी पर लटकने से दम घुटना बताया। जिस साड़ी से श्रीमती वर्मा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी, उस पर चिपकी खाल और बाल का मिलान करने से भी यह बात साफ हो गयी कि वे दोनों क्रमशः श्रीमती वर्मा के गर्दन और सिर के थे। खाल और बाल को रसायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित कर लिया गया। फंदा लगने से गले में पाया गया खरोंच का निशान अर्ध-चन्द्राकार था। इससे भी आत्महत्या की पुष्टि होती थी। शव पर जाहिर चोट का भी कोई निशान नहीं पाया गया।

अगले दिन प्रातः लोकदल (अ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा श्रीमती वर्मा के भाई अजीत सिंह और उनकी मां श्रीमती गायत्री देवी भी लखनऊ आ गयीं। श्रीमती वर्मा के बड़े पुत्र सुधीर को भी सूचना दे दी गयी। वह भी सेना के विशेष विमान द्वारा आ गया।

जुझारू व्यक्तित्व : स्व० श्रीमती सरोज वर्मा

आत्महत्या क्यों की ? : व्यापक जांच-पड़ताल तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अन्ततः पुलिस अधिकारियों ने इसे स्पष्ट आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया। परन्तु श्रीमती सरोज-वर्मा ने अपनी जीवन-लीला क्यों समाप्त कर ली? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनसे उन्हें आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ा? कहीं उन्हें किसी ने आत्महत्या के लिए मजबूर तो नहीं किया था? ऐसे कई सवाल आम नागरिकों और राजनीतिज्ञों में चर्चा का विषय बन गये हैं।

इस घटना के बाद अर्धविक्षिप्त अवस्था में अविनाश वर्मा को यह कहते सुना गया कि 'उसे राजनीति खा गयी।' जांच-अधिकारियों ने श्री वर्मा को ढ़ांढ़स बंधाते हुए कई सवाल किये। जिसके उत्तर में उन्होंने बताया, "छपरौली के कई जाट नेता सरोज पर इस बात का दबाव डाल रहे थे कि वह विधायक पद से इस्तीफा दे दें।" कारण पूछे जाने के बारे में श्री वर्मा का कहना था, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम-विवाह किया था, इसलिए उसकी बिरादरी के लोग उससे रुष्ट थे। वे लोग अक्सर उसके विरुद्ध कोई-न-कोई साजिश रचा करते थे, जिससे वह इस्तीफा दे दें। सरोज इससे काफी दुखी रहती थी।"

अविनाश वर्मा के अनुसार, "संभवतः इसी कारण उसने मौत को गले लगा लिया।" परन्तु लोकदल (अ) के कई नेताओं का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि श्रीमती सरोज वर्मा पर विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव पड़ रहा था।

इसके विपरीत श्रीमती वर्मा के एक निकटतम रिश्तेदार बताते हैं कि इस्तीफा देने की बात तो चल ही रही थी और इसके लिए ११ नवम्बर की तारीख भी तय हो गयी थी। तमाम लोगों में इस बात की उत्सुकता थी कि वे पार्टी-कार्यकर्ता कौन थे, जिनसे बातचीत करने के तत्काल बाद श्रीमती वर्मा ने आत्महत्या कर ली थी? श्रीमती वर्मा से उनकी क्या बातें हुई थीं? उनकी किसी बात से श्रीमती वर्मा को आघात तो नहीं लगा था?

विभिन्न अटकलें : इस बारे में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, "श्रीमती वर्मा से मिलनेवाले पांच युवकों मुन्ना सिंह (फैजाबाद), चौ० भोपाल सिंह (फतेहपुर), चन्द्रशेखर सिंह, राकेश सिंह और बब्बन सिंह रघुवंशी (तीनों बलिया) के थे। ये सभी युवा लोकदल (अ) के कार्यकर्ता थे। गत १५ अक्तूबर को विधानसभा में बमों के धमाके करके सनसनी फैलानेवाले दस युवकों में ये पांचों भी शामिल थे। पुलिस ने इन सभी को बम विस्फोट करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था।"

लोकदल (अ) के ही कुछ लोगों का कहना था कि जिन युवा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय में बम-विस्फोट किये थे, वे श्रीमती सरोज वर्मा के नजदीकी थे और संभवतः उन्हीं के इशारे पर इन युवकों ने बम-काण्ड को अंजाम दिया था। लोकदल (अ) के ही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस घटना से पार्टी की छवि काफी खराब हुई थी। बाद में पार्टी के लोगों ने श्रीमती वर्मा को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

इस संदर्भ में एक बात यह भी बताई जा रही है कि बम-काण्ड में गिरफ्तार इन कार्यकर्ताओं की जमानत के लिए अगले दिन अदालत में जब कोई छोटा-बड़ा नेता नहीं पहुंचा, तो इन युवकों ने गुस्से में कहा था, "पहले तो ये नेता लोग हंगामा करा देते हैं और बाद में फंस जाने पर अपना हाथ झाड़कर अलग हो जाते हैं।"

हजरतगंज कोतवाली के वे पुलिसकर्मी जो उस दिन अदालत में इन युवकों की जमानत से संबंधित कागजात आदि लेकर गये थे, बताते हैं कि उस समय इन कार्यकर्ताओं ने कचहरी में श्रीमती सरोज वर्मा को भी बुरा-भला कहा था।

बम-काण्ड को पार्टी के ही तमाम नेताओं और विधायकों ने अच्छा नहीं समझा। विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल सिंह यादव, जिनके कमरे में दो दिन बाद उसी तरह का एक बम मिला था, ने भी युवकों के इस कार्य को स्पष्ट समर्थन देने से इंकार कर दिया था।

लोकदल (अ) के कुछ नेताओं का कहना था कि श्रीमती वर्मा द्वारा की गयी आत्महत्या के अगले

दिन ही (२६ अक्तूबर को) पार्टी की लखनऊ में होने वाली प्रादेशिक कार्यकारिणी की बैठक में यह मामला उठाया जानेवाला था। उसी बैठक में बम-काण्ड को लेकर श्रीमती सरोज वर्मा से इस्तीफे की माग की जानेवाली थी। संभवतः इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली।

इसके विपरीत श्रीमती वर्मा से मिलने आये युवकों का कहना था कि वे सभी श्रीमती सरोज वर्मा से अपने-अपने जिलों के लिए दौरा कार्यक्रम तय करने गये थे। श्रीमती वर्मा ने उन्हें कार्यक्रम के लिए स्वीकृति भी दे दी थी। बम-काण्ड के विषय पर उस समय कोई बातचीत नहीं हुई थी। इन युवकों का यह भी कहना था कि श्रीमती वर्मा उस समय किसी भी तरह के तनाव में नहीं थीं।

लोकदल (अ) के विधायक शतरूद्र प्रकाश, श्रीमती सरोज वर्मा की आत्महत्या के पीछे 'बम काण्ड' के कारण को निराधार बताते हैं। वह कहते हैं, "श्रीमती वर्मा ने कभी भी हिंसक घटनाओं का समर्थन नहीं किया। इस तरह की मनगढ़ंत बातें निहित स्वार्थी तत्व फैला रहे हैं।

पार्टी के ही एक अन्य वर्ग का कहना है कि श्रीमती सरोज वर्मा पिछले कई दिनों से राजनीतिक रूप से अत्यधिक निराश थीं। गत १२ अक्तूबर को लखनऊ में हुई लोकदल (अ) की रैली में वे भाषण देने की उत्सुक थीं, परन्तु उनके भाई-अजीतसिंह ने उनको भाषण देने से यह कहकर मना कर दिया था कि इतने दिन चुप रही हो, तो आज भी चुप रहो। इस बात को मंच पर बैठे कई लोगों ने सुना था। उस रैली में कई अन्य विधायकों ने भाषण दिया था। इस बात से भी श्रीमती वर्मा काफी क्षुब्ध हो गयी थीं।

लोकदल (अ) के वयोवृद्ध नेता भूतपूर्व मंत्री अब्दुल रऊफ लारी का कहना था, "श्रीमती सरोज वर्मा इन दिनों पार्टी की कुछ गतिविधियों के कारण काफी परेशान रहती थीं। संभवतः आत्महत्या के पीछे यही कारण रहा होगा।"

लोकदल (अ) के विधायक मोहन सिंह इस बात से असहमति व्यक्त करते हैं। उनका कहना है, "इस समय पार्टी में उनकी बात का सभी आदर करते थे। वे तो उस समय भी दुखी नहीं हुई थीं, जब प्रदेश में पार्टी पर मुलायम सिंह का गुट हावी था तथा राजेन्द्र सिंह जैसे व्यक्ति को जो श्रीमती वर्मा के समर्थक थे, पार्टी से निकाल दिया गया था। इस समय तो उनके भाई ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर पार्टी की किन गतिविधियों से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी।

पारिवारिक कारण: अधिकांश पुलिस अधिकारी इसे 'पारिवारिक कलह' का परिणाम बताते हैं। वे कहते हैं, जब उनके पति सामान्य स्थिति में होंगे, तभी पूछताछ के बाद किसी स्पष्ट कारण का पता किया जा सकता है।

वरिष्ठ चिकित्सा विधि विशेषज्ञ डा० के०के० सिंघल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि श्रीमती वर्मा ने मानसिक तनाव के दौरान आत्महत्या की, क्योंकि वे 'लो ब्लडप्रेशर' की मरीज थीं और तीन बार पहलें भी बेहोश हो चुकी थीं। चिकित्सा विधि विशेषज्ञों का कहना था कि श्रीमती वर्मा भले ही पारिवारिक कलह से परेशान रही हों, परन्तु कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद उनका आत्महत्या करना, यह स्पष्ट करता है कि उन्हें राजनीति की किसी बात से सदमा पहुंचा था और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। यही कारण है कि उन्होंने जल्दी में लिये गये निर्णय की वजह से आत्महत्या से पूर्व कोई पत्र भी नहीं लिखा। विधि-विशेषज्ञ बताते हैं कि श्रीमती वर्मा बाथरूम में नहाने के उद्देश्य से गयीं थीं, क्योंकि उन्होंने पानी गर्म किया था तथा कपड़े भी साथ ले गयी थीं। बाथरूम में ही अचानक उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया होगा।

इसी बीच लोकदल (अ) के एक अन्य प्रादेशिक महामंत्री तथा मिर्जापुर के विधायक यदुनाथ सिंह ने प्रदेश के गृहसचिव से भेंटकर कहा, "यह मामला आत्महत्या का है। इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं, इसलिए सारे पहलुओं की बारीकी से जांच करायी जाये।"

लोकदल (ब) के प्रादेशिक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव इस आत्महत्या की घटना के पीछे श्रीमती वर्मा की राजनीतिक निराशा को कारण मानते हैं। वह कहते हैं, "सरोज की अजीत सिंह से पट नहीं रही थी। इसी से खिन्न होकर सरोज वर्मा ने आत्महत्या कर ली है।"

श्रीमती वर्मा का जन्म २३ फरवरी, १९३७ को गाजियाबाद में हुआ था। वह एम०ए० पास थीं। ५ दिसम्बर, १९५५ को उन्होंने अपने पिता चौधरी चरण सिंह की मर्जी के विरुद्ध अविनाश चन्द्र वर्मा से प्रेम-विवाह किया था। शादी के बाद काफी समय तक पिता-पुत्री में मनमुटाव रहा, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो गया था।

> पुलिस को कमरे से चालू वर्ष की ऐसी कोई डायरी भी नहीं मिली, जिसमें श्रीमती वर्मा द्वारा डायरी लिखी जाती थी, जबकि पिछले वर्षों की डायरियां उनके कमरे में मौजूद थीं। श्रीमती वर्मा का शव भी परिवारवालों ने फंदे से निकाल लिया था, जिससे वास्तविक स्थिति का आकलन करने में पुलिस को कठिनाई हो रही थी।

मार्च, १९८५ के विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र छपरौली से लोकदल के उम्मीदवार के रूप में उन्हें खड़ा किया था। उस चुनाव में श्रीमती वर्मा ३३,६३२ मत प्राप्त कर विजयी हो गयी थीं।

चौधरी साहब के निधन के बाद जब लोकदल दो हिस्सों में बंटा, तो श्रीमती वर्मा अपने भाई अजीत सिंह के साथ हो गयीं। उन्हें लोकदल (अ) का प्रादेशिक महामंत्री बना दिया गया।

वसीयत विवाद का संदेह: लोकदल (अ) के एक प्रमुख पदाधिकारी इस आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताते हैं। वह कहते हैं, "मामला चरण सिंह की सम्पत्ति की वसीयत का है। चौधरी साहब, सरोज को बहुत अधिक चाहते थे, जबकि गायत्री देवी अजीत सिंह को चाहती हैं। जिन दिनों चौधरी साहब बीमार थे, तो वह अपनी सम्पत्ति की वसीयत करके कुछ हिस्सा सरोज को देना चाहते थे, लेकिन मां-बेटे इसका विरोध करते रहे। जिस तरह से चौधरी साहब के अंगूठे का निशान बनवाकर लोकसभा सचिवालय को उनकी बीमारी की अवधि का वेतन देने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया था, उसी तरह के अंगूठे के निशान बनवाकर मां बेटे ने चौधरी साहब से कोई ऐसी वसीयत करा ली थी, जिसमें सरोज वर्मा को कोई सम्पत्ति नहीं दी थी।

लोग बताते हैं कि इसी के बाद से सरोज और अजीत में मनमुटाव शुरू हो गया। आत्महत्या से पूर्व की परिस्थिति का जिक्र करते हुए सरोज वर्मा के एक नजदीकी रिश्तेदार यह संभावना प्रकट करते हैं, "जब सरोज नहाने के लिए बाथरूम में गयी होगी, तो उसी समय कोई फोन आया होगा। फोन सरोज की देवरानी ने रिसीव किया होगा। फोन करनेवाले ने संभवतः उनकी देवरानी से कहा होगा कि कल अजीत लखनऊ आ रहे हैं, सरोज से कह दो वह अजीत से वसीयतवाले मामले का खुलासा कर लें।"

संभवतः उसी समय सरोज वर्मा अपनी देवरानी से वाराणसी स्टेशन पर मिलनेवाली बात कहने के लिए बाथरूम से निकली होंगी। तभी देवरानी ने फोन पर मिले संदेश को बताया होगा। इसी के बाद सरोज वर्मा मानसिक रूप से असंतुलित हुई होंगी और दोबारा बाथरूम में घुसते ही उन्होंने इस संसार से विदा हो जाने का निर्णय ले लिया होगा।

लेकिन, गायत्री देवी वसीयतवाली बात का पूरी तरह खण्डन करती हैं। वह कहती हैं, "मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सरोज ने आत्महत्या क्यों की। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी।"

बहरहाल, परिवारवाले, रिश्तेदार, पार्टी-कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी सभी अपने-अपने तरीकों से आत्महत्या का वास्तविक कारण जानने के प्रयास में हैं। देखना है कि इस रहस्यमय आत्महत्या के वास्तविक कारण का पता चलता भी है या समय बीतने के साथ-साथ यह प्रकरण रहस्य के गर्त में दब जाता है।

—स्वदेश कुमार

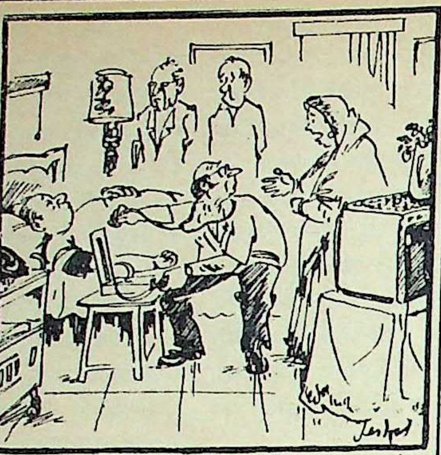

डाक्टर, इसका कारण 'वनडे' मैच नहीं है...उन्हें किसी भी क्षण होनेवाले मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की प्रतीक्षा है...

व्यंग्यकार : केशव
'हिंदु' से साभार

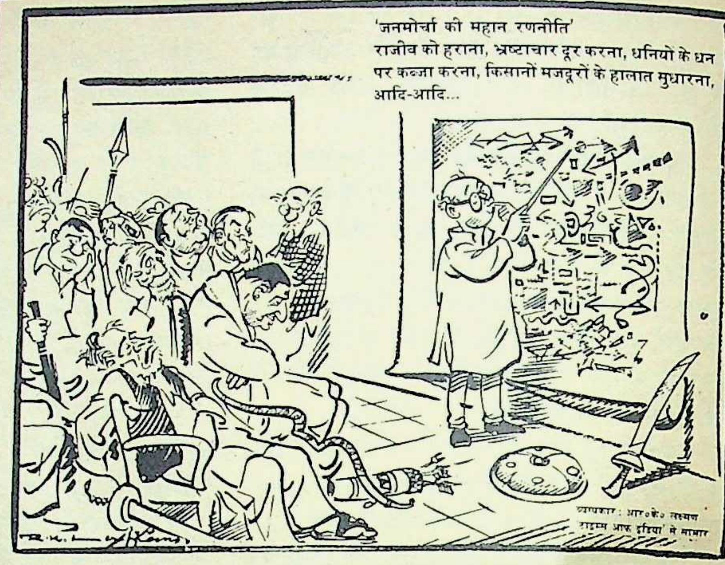

'जनमोर्चा की महान रणनीति'
राजीव को हराना, भ्रष्टाचार दूर करना, धनियों के धन पर कब्जा करना, किसानों मजदूरों के हालात सुधारना, आदि-आदि...

व्यंग्यकार : आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' से साभार

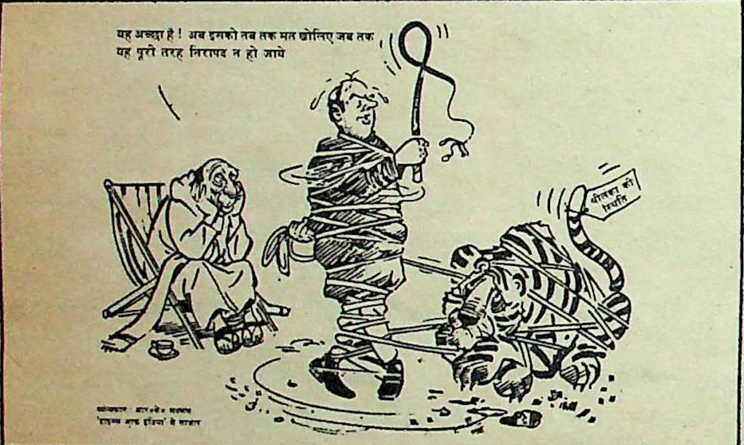
यह अच्छा है ! अब इसको तब तक मत खोलिए जब तक यह पूरी तरह निरापद न हो जाये
श्रीलंका की स्थिति

व्यंग्यकार : आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' से साभार

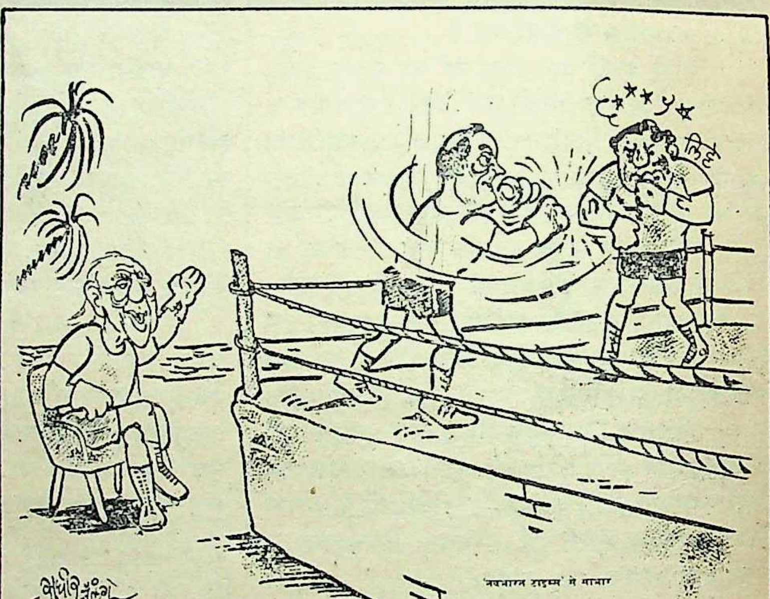

'नवभारत टाइम्स' से साभार

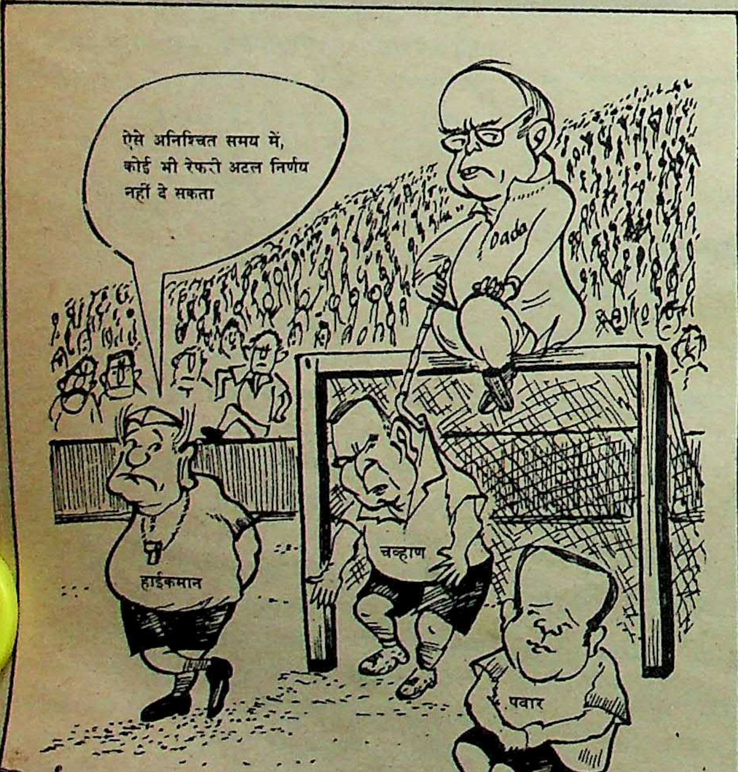
ऐसे अनिश्चित समय में, कोई भी रेफरी अटल निर्णय नहीं दे सकता
Dada
हाईकमान
चव्हाण
पवार

'हिंदू' से साभार
व्यंग्यकार : उन्नी

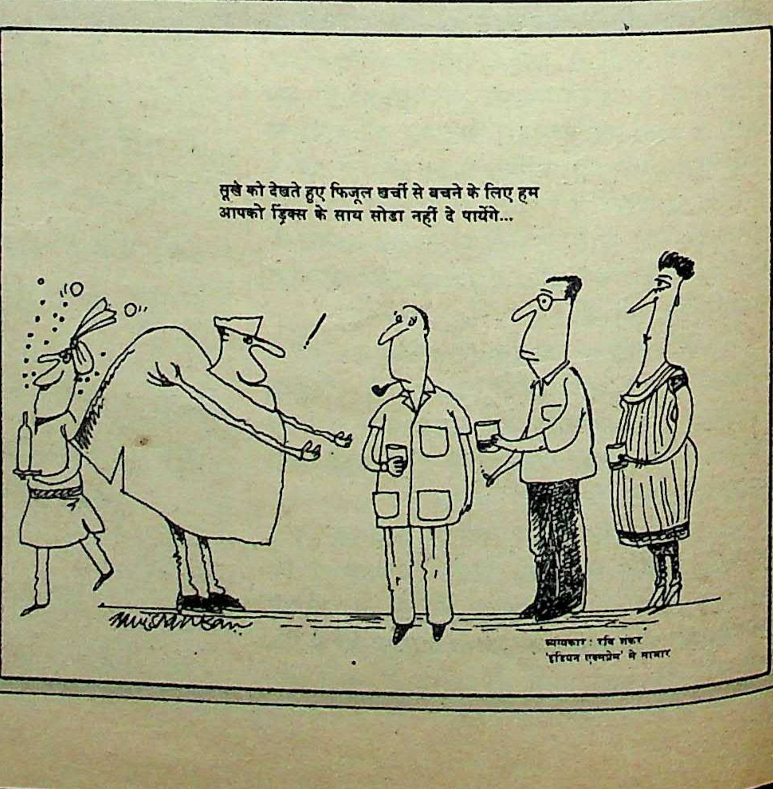
सूखे को देखते हुए फिजूल खर्ची से बचने के लिए हम आपको ड्रिंक्स के साथ सोडा नहीं दे पायेंगे...

व्यंग्यकार : रवि शंकर
'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार

औरंगाबाद :

एक नरसंहार की छमाही

छह महीने पूर्व औरंगाबाद जिले के बघौरा और दलेलचक गांवों में ५४ लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। तब सुरक्षा, राहत और विकास कार्यक्रमों की जो सरकारी घोषणाएं हुईं, वे सब कागजी बनकर रह गयीं। खोखली पुलिस व्यवस्था और पिछड़ेपन के शीर्ष पर लटके औरंगाबाद जिले के निवासी इस आशंका से भयभीत हैं कि पता नहीं कब किस गांव में दलेलचक-बघौरा के प्रतिशोध में उससे भी बड़ा रक्तपात न हो जाये। इस इलाके में व्याप्त भय, आशंका और धधक रही प्रतिशोध की आग का जायजा विकास कुमार झा द्वारा :

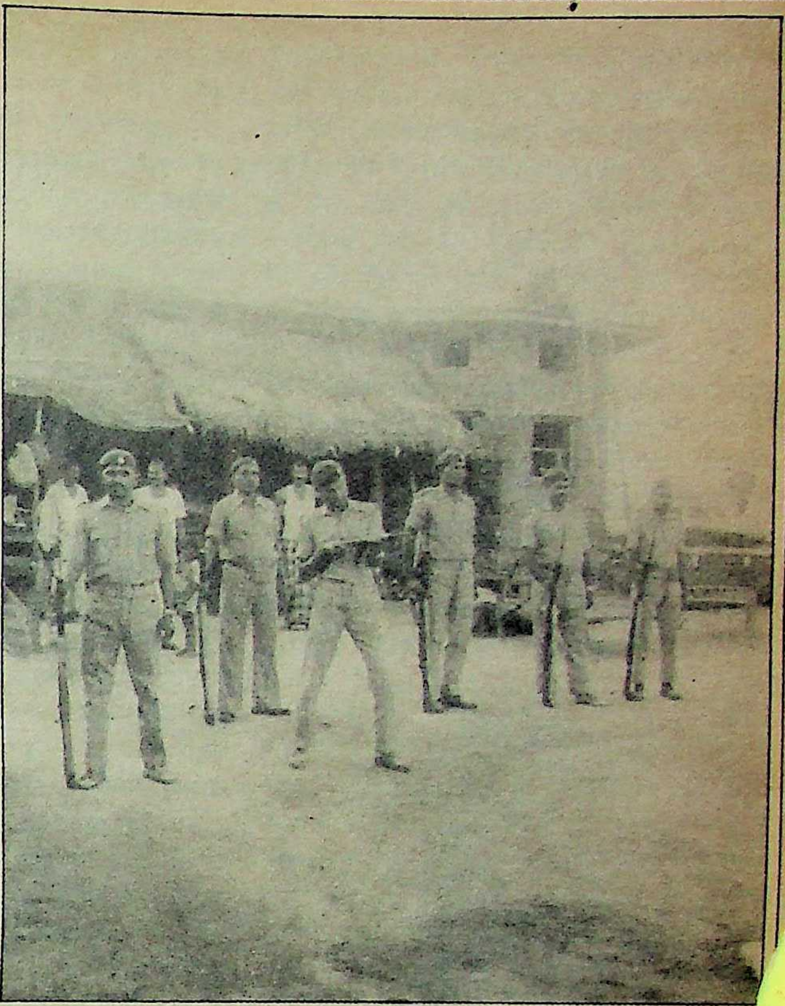

क्या पुलिस रक्षा कर सकेगी ? : बघौरा गांव में त्रिवेणी सिंह के घर में पुलिस बल

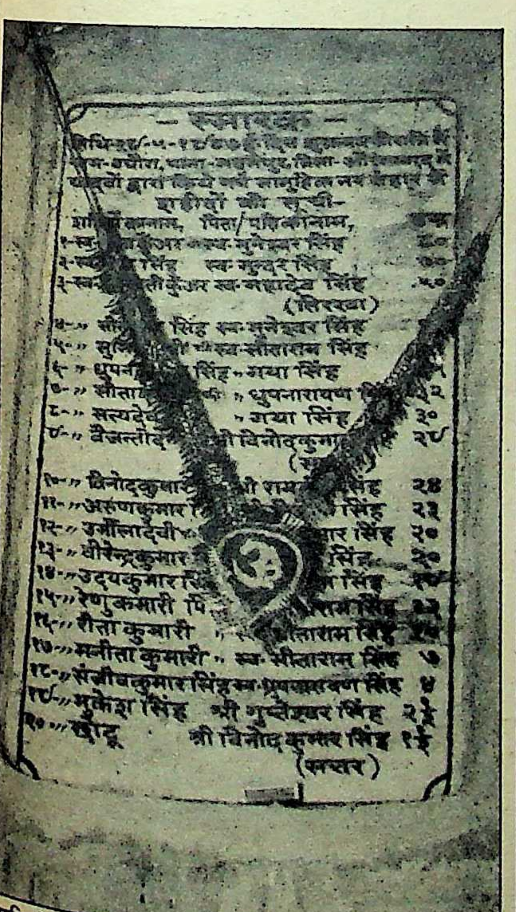

प्रतिशोध की प्रेरणा : त्रिवेणी सिंह के घर में मृतकों का स्मारक

इतिहास के कटुतम प्रसंगों को रेखांकित करने का एक ही सुगम और सटीक रास्ता है कि अराजकता की उन तारीखों को छठे-छमासे याद कर लिया जाये, जो किसी भी सरकार के लिए कलंक हैं। २६ नवंबर, '८७ को ऐसी ही एक खौफनाक तारीख की छमाही है। २६ मई को बिहार का भीषणतम नरसंहार यानी औरंगाबाद का दलेलचक-बघौरा कांड हुआ था। इस कांड में ५४ लोगों ने प्राण गंवाये थे। दलेलचक गांव के ७० वर्षीय वृद्ध रामेश्वर सिंह कहते भी हैं, "छह माह पहले तीर्थस्थल बन गया था हमारा गांव ! कौन नहीं आये ? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, बूटा सिंह, बिन्देश्वरी दुबे तक सभी आये, पर इलाके की किस्मत नहीं बदली।"

सचमुच आज से छह माह पूर्व औरंगाबाद के ये दो गांव सुर्ख मुद्दे बन गये थे। मुख्यमंत्री दुबे की विफलता का जीता जागता नमूना। युद्धस्तर पर औरंगाबाद के इन दीन-हीन गांवो की दशा-सुधार का ऐलान किया गया, पर आज तक कुछ भी नहीं बदला है। गांवों तक आज भी सड़कें नसीब नहीं हो पायी हैं और न ही अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएं पहुंच सकी हैं।

सरकार सोयी है : ऊपरी तौर पर भले ही औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके खामोश हैं, पर यह खामोशी अमन का संकेत नहीं, आसन्न विस्फोट का मौन कंपन है। सही मायने में उस भीषणतम नरमेध के तत्काल बाद हायतौबा मचाने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। औरंगाबाद के आरक्षी अधीक्षक अनिल कुमार सिन्हा भी परोक्ष रूप से इन बातों को स्वीकारते हुए कहते हैं, "समझ में नहीं आता, तमाम समस्याओं व विफलताओं की जिम्मेदारी अकेले पुलिस पर ही क्यों थोप दी जाती है। खतरे की आशंका आज भी है और यही आशंका हमें अपने काम में तत्पर रखे हुए है। जब तक औरंगाबाद के गांव-गांव में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव रहेगा पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। औरंगाबाद विकास के मामले में अंतिम दर्जे पर है। आर्थिक असमानता, मजदूरी के सवाल, सड़क, सिंचाई, बिजली, शिक्षा यह सब सुविधा पुलिस तो नहीं जुटा सकती। मेरे कार्यकाल में ग्यारह पुलिस पिकेट्स बढ़े हैं। पहले ३५ थे अब ४६ पिकेट्स हैं। रही बात भय और आतंक की तो जहां इतने लोग मारे जा चुके हैं, वहां इतनी जल्दी भय खत्म नहीं होने वाला।" अनिल के मुताबिक उनके कार्यकाल में अभी तक ४७० उग्रवादी पकड़े गये हैं, पर दलेलचक-बघौरा तथा दरमिया नरसंहार से संबंधित उग्रवादी जिन पर बिहार सरकार ने पचास-पचास हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है, अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ सके, इसका कोई उत्तर आरक्षी अधीक्षक अनिल सिन्हा के पास नहीं है। सचमुच, अनिल एक ऐसे विवश आरक्षी अधीक्षक हैं जो औरंगाबाद पुलिस की विपन्नता का रोना भी नहीं रो सकते। औरंगाबाद जिले में कुल १६ थाने

हैं। इनमें कुछ गिनेचुने थाने ही ऐसे भाग्यशाली हैं, जिनका अपना भवन है। अधिकांश थाने बगैर भवन के हैं। नतीजतन, थाने में नियुक्त आरक्षी व सशस्त्र बल कहां रहे यह एक स्थायी समस्या बनी हुई है। उग्रवादियों पर काबू पाने के इरादे से खुले सभी ४६ पुलिस पिकेट्स भवनविहीन हैं। एक पिकेट में औसतन, तीन हवलदार, बारह सिपाही और एक सब इंसपैक्टर होते हैं। सभी पिकेट्स के आरक्षी टेण्ट लगाकर या गांव के ही किसी व्यक्ति के दालान में महीनों से जमे हुए हैं। दलेलचक-बघौरा कांड के पूर्व ही गया के आयुक्त ने 'स्पेशल एरिया प्रोग्राम' के अंतर्गत रफीगंज, मदनपुर तथा देव थाना क्षेत्र में पडनेवाले पुलिस पिकेटों पर भवन निर्माण का आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त जिले के अन्य क्षेत्रों में भीएन०आर०इ०पी०के तहत थाने के भवन निर्माण का आदेश हुआ था, पर अभी तक कसमा और देव थाना को छोडकर बक्शी बिंगहा, चिरैला, छोटकी छेछानी तथा सलैया पुलिस आउटपोस्ट भवनहीन हैं। वाहन की भी स्थिति यही है। कुछ ही थाने पर जीप सुलभ है। वह भी सिर्फ एक और तिस पर मरम्मत के अभाव में बेकार। निर्णय हुआ था कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से इन गाड़ियों की मरम्मत होगी। पर जाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं होना था। वायरलेस सेटों की भी ऐसी ही स्थिति है। न किसी थाने पर वायरलेस सेट सुलभ है न ही वायरलेस आपरेठर। जबकि कायदे से हर थाने व हर पुलिस पिकेट पर वायरलेस सेट होना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के आसन्न खतरे को टालने के लिए हर स्तर पर सम्पर्क साधा जा सके। मदनपुर थाना जिसके तहत दलेलचक—बघौरा गांव स्थित है के पास सिर्फ एक ही जीप है। पुलिस बल की भी स्थिति दयनीय है। मदनपुर थाने में एक इंसपैक्टर के अलावा बस एक हवलदार और एक सिपाही है, जबकि कम से कम आठ सिपाही तो सामान्य स्थिति में होने चाहिए। थाने पर जो इकलौता सिपाही है, वही जूता सिलाई से चंडी पाठ तक करता है। यानी मुद्दालेह को कचहरी पहुंचाने से लेकर डाक आदि लाने-पहुंचाने तक का काम उसी के जिम्मे है।

अनिल सिन्हा

आरक्षी अधीक्षक अनिल सिन्हा के मुताबिक उनके कार्यकाल में अभी तक ४७० उग्रवादी पकड़े गये हैं, पर दलेलचक-बघौरा तथा दरमिया नरसंहार से संबंधित उग्रवादी, जिन पर बिहार सरकार ने पचास-पचास हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है, अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ सके, इसका जवाब अनिल सिन्हा के पास नहीं है।

कुल मिलाकर खोखली पुलिस व्यवस्था और पिछड़ेपन के शीर्ष पर लटके औरंगाबाद के गांवों में दुखद आशंकाओं के सिवा और क्या संभव है। 'प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन' के महासचिव सारंगधर पासवान सशंकित हैं कि एम०सी०सी० और आई०पी०एफ० की भूमिगत सक्रियता मदनपुर थाने के गांवों में कभी भी कुछ करवा सकती है। पिछले छह माह से औरंगाबाद पर खतरनाक आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं कब किस गांव में दलेलचक-बघौरा का जवाबी रक्तपात हो जाये।

नामजद आतंकवादी अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। ऐसे में कैसे कहा जाये कि स्थिति नियंत्रण में है। छोटकी-छेछानी कांड में ५० लोग और दलेलचक-बघौरा कांड के सिलसिले में सौ से भी अधिक लोग गया और औरंगाबाद जेल में बंद हैं। धीरे-धीरे जब ये छूटेंगे, हवा का रुख और बिगड़ेगा।

राम नरेश सिंह

दलेलचकबघौरा में हुए रक्तपात के कारणों की तहकीकात व उसके निदान हेतु उपाय सुझाने के लिए बिहार सरकार ने पांच सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन ग्रामीण विकास मंत्री सिद्धेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में किया था। इस उपसमिति ने चार माह पूर्व अपना प्रतिवेदन सरकार को दे भी दिया, पर उपसमिति की तमाम अनुशंसाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। सिद्धेश्वर प्रसाद को खुद भी पता नहीं कि उन अनुशंसाओं की क्या स्थिति है। वे कहते हैं कि प्रतिवेदन में उपसमिति ने हर स्तर पर पुलिस को सशक्त व सतर्क करने पर बल दिया था। पुलिसबल की वृद्धि के साथ ही पुलिस को तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गयी थी। साथ ही वायरलेस सेट तथा वाहन सुलभ कराने की अनुशंसा की गयी थी। यह पूछे जाने पर कि औरंगाबाद में कहीं भी अपेक्षित संख्या में जीप या वायरलेस सेट उपलब्ध नहीं हैं, सिद्धेश्वर कहते हैं कि वायरलेस सेट के लिए कलकत्ता या पंजाब की किसी कंपनी को आदेश दिया हुआ है, देखें कब तक इसकी आपूर्ति हो पाती है। जीप आवंटन का भी आदेश जीप बनानेवाली एक कंपनी को भेजा गया है, पर इस सब में कुछ समय लगेगा ही।" गृहमंत्री बूटा सिंह ने भी दलेलचक-बघौरा आकर घोषणा की थी कि औरंगाबाद के पिछड़ेपन की रिपोर्ट वह सीधे प्रधानमंत्री को देंगे, पर बूटा के उस रस्मी बयान को औरंगाबाद के आम लोग सच मान बैठे।

मलबे के गांव: सही मायने में दलेलचक-बघौरा नामक दोनों गांवों का अब कोई अस्तित्व नहीं। जले और ढहे हुए घरों के मलबे को अगर गांव माना जा सकता हो, तभी इन दोनों गांवों के अस्तित्व को स्वीकारा जा सकता है। बघौरा गांव में तो अब कोई नहीं रहता। रक्तपात में मारे गये गया सिंह, लखन सिंह आदि के जले हुए मकानों का बस मलबा बचा है। गांव में त्रिवेणी सिंह का मकान पक्का होने के कारण नष्ट नहीं हो पाया था। इसी में पुलिस पिकेट का पड़ाव है। त्रिवेणी सिंह के घर में भी अब कोई नहीं बचा है। त्रिवेणी सिंह संयोग से बच गये थे क्योंकि वह बाहर नौकरी करते रहे हैं। वह भी अब भूले-भटके ही गांव पहुंच पाते हैं। गया सिंह की विधवा अकेले गांव में कैसे रहती, सो वह भी कुजु

कोलियरी के पास रह रहे अपने बेटी-दामाद के पास चली गयी। बघौरा के पड़ोसी गांव के वृद्ध रविदास क्षुब्ध होकर कहते हैं, "बघौरा गांव तो मिट गया बाबू! क्या आपको लगता है फिर कभी आबाद हो पायेगा यह गांव?" त्रिवेणी सिंह ने अपने मकान में (अभी पुलिस पिकेट्स का डेरा है) अपने मृत २० स्वजनों की स्मृति में संगमरमर के पत्थर पर नाम अंकित करवाकर लगवा दिया है। उस स्मारक पर एक माला पड़ी है। अगर कभी बघौरा गांव दोबारा आबाद हुआ, तो संगमरमर के पत्थर पर गुदे ये नाम वहां की कई पीढ़ियों के मन को उद्विग्न करते रहेंगे।

दलेलचक गाव की भी कमोबेश यही स्थिति है। इस गांव का अमरेश सिंह उस रक्तपात में अपने परिवार के सात परिजनों पिता जगदेव सिंह, मा रजनानी देवी, चाचा नागदेव सिंह व देवन सिंह, भाई कांता सिंह और उनकी पत्नी तथा पुत्री गुड़िया को गंवा चुका है। अमरेश दलेलचक में अब नहीं रहता। एक कोस की दूरी पर आंजन गांव के जगदीश सिंह के घर पर वह पत्नी सहित शरण लिए हुए है। प्रत्येक दिन वह आंजन से दलेलचक आकर एकाध घंटे खेती का काम देख लेता है। अमरेश कहता है, "दलेलचक की जो थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन बची है, वह अगर कोई खरीदने को तैयार हो तो बेचकर मैं हमेशा के लिए इस जगह से छुट्टी पाना चाहता हूं। उग्रवादियों से मेरी जान को अभी भी खतरा है।" दलेलचक गांव की सीमा पर जहां पुलिस पिकेट है, ठीक उसके बगल में अमरेश ने अपने मृत सातों स्वजनों की स्मृति में स्मारक बना रखा है। वह कहता है, "जीते जी न सही कम से कम मरने के बाद बने स्मारक की रक्षा तो पुलिस कर रही है।" दलेलचक पुलिस पिकेट के जवान शिकायत करते हैं कि यहां उन्हें एक लालटेन तक सुलभ नहीं करायी गयी है। टेण्ट में किसी तरह समय काट रहे हैं। दलेलचक के ही एक वृद्ध रामेश्वर सिंह, जिनके परिवार के अधिकांश लोग मौत के घाट उतर गये, कहते हैं, कि रहने के लिए हमारे पास कोई घर नहीं। मुख्यमंत्रीजी ने वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने का आश्वासन दिया था पर कुछ भी नही मिला। रामेश्वर सिंह के भाई धनेश्वर सिंह तो पूरे परिवार सहित मारे गये, पर धनेश्वर की चार लड़कियां कभी-कभार आकर अपने दिवंगत पिता की जमीनों की खेती जो बटाई पर है, का हिसाब-किताब देखती हैं।

> बघौरा के पड़ोसी गांव के वृद्ध रविदास क्षुब्ध होकर कहते हैं, "बघौरा गांव तो मिट गया बाबू। क्या आपको लगता है, फिर कभी आबाद हो पायेगा यह गांव।" अगर कभी बघौरा गांव दोबारा आबाद हुआ, तो संगमरमर के पत्थर पर खुदे ये नाम वहां की पीढ़ियों के मन को उद्विग्न करते रहेंगे।

रामेश्वर सिंह

मृतकों का स्मारक

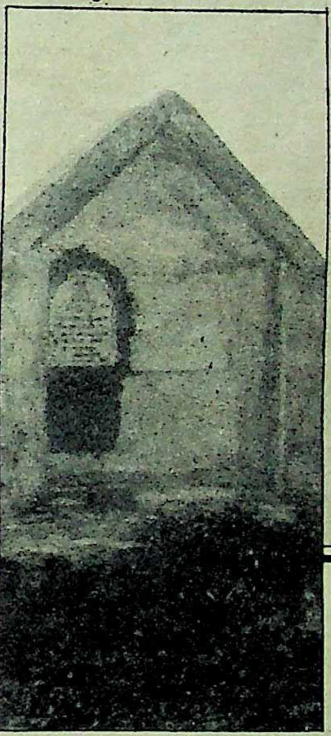

> दलेलचक के ही एक वृद्ध रामेश्वर सिंह, जिनके परिवार के अधिकांश लोग मौत के घाट उतर गये, कहते हैं कि रहने के लिए हमारे पास कोई घर नहीं। मुख्यमंत्रीजी ने वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने का आश्वासन दिया था, पर कुछ भी नहीं मिला। उसके भाई धनेश्वर सिंह तो पूरे परिवार सहित मारे गये।

औरंगाबाद के पूर्व विधायक रामनरेश सिंह दलेलचक-बघौरा कांड के बाद काफी सुर्खी में आये थे। नरसंहार के ठीक अट्ठारह दिन बाद १६ जून को रामनरेश की गिरफ्तारी इस आरोप में हुई थी कि वह इलाके के राजपूतों को जवाबी रक्तपात के लिए उकसा रहे हैं। आखिरकार ४५ दिन बाद ही रामनरेश जेल से छूट सके थे। रामनरेश कहते हैं, "नामजद आतंककारी रामदास यादव, संजय दुसाध, सूबेदार यादव और पुरुषोत्तम यादव जिन पर इनाम भी घोषित हैं पकड़े नहीं जा सके हैं। ऐसे में कैसे कहा जाये कि स्थिति नियंत्रण में है। छोटकी-छेछानी कांड में ५० लोग और दलेलचक-बघौरा कांड के सिलसिले में सौ से भी अधिक लोग गया व औरंगाबाद जेल में बंद हैं। धीरे-धीरे जब ये छूटेंगे तो हवा का रुख और बिगड़ेगा।" पूर्व सांसद और 'जनमोर्चा' के नेता शंकर दयाल सिंह (धनबाद-ब्रांड नहीं) कहते हैं कि उस सघन गिरफ्तारी में कुछ निरपराध लोग भी जेल के भीतर कर दिये गये। पर सिर्फ दलेलचक-बघौरा ही नहीं औरंगाबाद थाने के दरमिया और पारसडीहा गांव आतंक व बदहाली से गुजर रहे हैं। पारसडीहा में छह लोग और दरमियां में ग्यारह लोगों का गला रेता गया था। दरमिया गांव आज भी पहुंचना दुष्कर है। कई नदी-नालों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से लंबी पदयात्राका भगीरथ प्रयास करने के बाद ही वहां पहुंचा जा सकता है। दरमिया में जब नरसंहार हुआ था, तो काफी अफरातफरी मची थी, पर वह बदनसीब गांव रत्तीभर भी विकास की सरकारी खैरात नहीं पा सका।

छह महीने—साल फिर साल-दर-साल...। कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे औरंगाबाद के इंका सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह हों या औरंगाबाद विधानसभाई क्षेत्र के इंका प्रतिनिधि बृजमोहन सिंह हों, सबकी गाड़ी चलती रहती है, बाकायदा। राजनीतिक प्राणियों के लिए वहशी तारीखें बेमानी हैं, और औरंगाबाद की यतीम ग्रामीण आबादी के लिए इन तारीखों की याद में जीना एक मजबूरी। वह इसलिए कि हादसे जिन कारणों से होते हैं, वे खूंटे की तरह अपनी जगह गड़े हुए हैं और इन कारणों से बंधे रहने की नियति को सरकार खत्म नहीं कर पाती। उसमें भी तब जबकि सूबे में बिन्देश्वरी दुबे की सरकार हुकूमत कर रही हो।

—विकास कुमार झा
छाया: दीपक कुमार

मधुर पल की
मधु मुस्कान

nutrine Chocolate Eclairs

गाढ़े क्रीमदार
चॉकलेट एक्लेयर्स
की शान

न्यूट्रीन
के स्वाभाविक रूप

ज्यादा दूध, ज्यादा मक्खन,
ज्यादा चॉकलेट.

न्यूट्रीन—भारत में सबसे ज्यादा
बिकनेवाला चॉकलेट

ही माँगिये

nutrine Chocolate Eclairs

nutrine

CLARION/NC/8726/HIN

मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के पुत्र दिनेश जोशी पर उछले इस आरोप ने राजस्थान राजनीति में एक नयी हलचल मचा दी है कि उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप नीमरोट को परिवहन या आबकारी अधिकारी नियुक्त करवाने के लिए ७० हजार रुपए की रिश्वत ली और काम न होने पर जब नीमरोट ने रुपए वापस मांगे, तो उनकी हत्या करवा दी। कुछ अर्सा पहले हुए 'वकील हत्याकांड' में भी ऐसा ही आरोप मुख्यमंत्री-पुत्र पर लगा था। सती कांड में मुख्यमंत्री जोशी की काफी छीछालेदर हो चुकी है और अपने पुत्र को उक्त आरोप से पाक-साफ करने के लिए कुछ न करने से श्री जोशी पर ही यह आरोप लग रहा हैं कि वह खुद भी इस प्रकरण में शामिल हैं। भ्रष्टाचार और हत्या का यह आरोप मुख्यमंत्री के पुत्र पर क्यों लगाया जा रहा है?

मुख्यमंत्री के पुत्र पर हत्या का आरोप

भ्रष्टाचार का शिकार:
स्व० कुलदीप सिंह
नीमरोट (मीणा)

जब पूरा देश राजस्थान के सीकर जिले में हुए स्त्री-दहन पर आन्दोलित था, तभी आयोजित विधान सभा सत्र में २६ सितम्बर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक डा० करोड़ीमल मीणा ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की रिपोर्ट के मसले पर हुई चर्चा क़े दौरान आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के बड़े पुत्र दिनेश जोशी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी कुलदीप निमरोट (मीणा) से 'मनचाहे-पद' पर नियुक्ति के आश्वासन के बदले ७० हजार रुपए रिश्वत के रूप में लिये। श्री जोशी इस आरोप के समय दिल्ली में आलाकमान की हाजिरी बजा रहे थे, तो विपक्ष के नेता भैरोंसिह शेखावत सदन से बाहर लन्दन से लौटने की थकान मिटा रहे थे। दोनों की अनुपस्थिति का नतीजा यह हुआ कि मीणा का आरोप विधान सभा में बम के धड़ाके की तरह गूंजा, पर अगले दिन अखबारों में खबर से आगे नहीं बढ़ सका।

मुख्यमंत्री पर लगा आरोप ४८ घण्टे बाद बेअसर सा नजर आने पर माया ने आरोप की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। यह आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री के पुत्र पर एक वकील सुरेश गुप्ता को राजस्व मण्डल का सदस्य बनवाने के लिए राज्यसेवा के एक न्यायिक अधिकारी के माध्यम से रिश्वत का मामला सामने आया था। उस मामले में उक्त न्यायिक अधिकारी पर रिश्वत के पैसे वापस मांगने वाले वकील की हत्या कर देने का आरोप है। उक्त अभियुक्त अधिकारी पर सी०बी०आई० द्वारा दिल्ली स्थित न्यायालय में आज भी मुकदमा चल रहा है।

राज्यपाल को पत्र: विधान सभा में भाजपा विधायक डा० करोड़ीलाल मीणा के आरोप का असर न होने पर, उन्होंने अपने ही दल के विधायक हरीश शर्मा के साथ मिलकर एक अक्तूबर को एक पत्र राज्यपाल वसन्त दादा पाटील को लिखा। पत्र में आरोप है, "मुख्यमंत्री श्री जोशी के सुपुत्र दिनेश जोशी द्वारा जनसाधारण व अधिकारियों को पदस्थापन, स्थानांतरण व पदोन्नति का प्रलोभन देकर रुपए ऐंठे जाते हैं।" पत्र में यह भी कहा गया, "किसी तकनीकी व्यवधान या केन्द्र के हस्तक्षेप के कारण जब वह ऐसे कार्य को पूर्ण नहीं करा पाते हैं, तो उस व्यक्ति को रुपए लौटाने की अपेक्षा मरवा दिया जाता है।" प्रशासनिक अधिकारी नीमरोट के मामले का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा गया, "कुलदीप नीमरोट पांच वर्ष पूर्व कुशलगढ़ में एस०डी०ओ० थे तथा इसके बाद बांसवाड़ा में (मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र) भी एस०डी०ओ० रहे। जिस समय नीमरोट वहां कार्यरत थे, उनकी दोस्ती मुख्यमंत्री के लड़के दिनेश जोशी व बांसवाड़ा के जिला प्रमुख पवन कुमार रोकड़िया से हुई।" प

के अनुसार, "यह दोस्ती उस वक्त काम आयी, जब नीमरोट का तबादला धौलपुर कर दिया गया। नीमरोट ने धौलपुर न जाने की बात दिनेश जोशी से कही, तो उन्होंने कहा बताया, "यदि रुपए खर्च करो, तो आपको आर०टी०ओ० (परिवहन अधिकारी) जयपुर या जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर लगवा दूंगा। नीमरोट इसके लिए तैयार हो गये और उन्होंने तीस हजार रुपए मुख्यमंत्री के पुत्र को दिये, जिसे उसने कम बताया तो बीस हजार रुपए और दिया। पचास हजार रुपए पहुंचने के बाद दिनेश जोशी ने अपनी मांग एक लाख रुपए कर दी। नीमरोट बाकी के पचास हजार में से २० हजार रुपए और लेकर जब बांसवाड़ा पहुंचे, तो दिनेश जोशी नहीं मिले। इस बार यह रुपए दिनेश जोशी को देने के लिए बांसवाड़ा के जिला प्रमुख पवन कुमार रोकड़िया को देकर नीमरोट लौट आये। इस बीच नीमरोट का स्थानांतरण धौलपुर से सिरोही हो गया।"

मनचाहे पद पर स्थानांतरण न होने पर नीमरोट बांसवाड़ा जाकर श्री दिनेश जोशी से मिले। राज्यपाल को लिखे पत्र में बताया गया है कि कई बार चक्कर लगाने के बाद दिनेश जोशी ने कहा बताया कि तीस हजार रुपए और दे दो, तो आर०टी०ओ० (परिवहन अधिकारी) जयपुर के पद पर नियुक्ति करवा दूंगा। जवाब में नीमरोट का कहना था पदस्थापन के तुरन्त बाद बाकी की रकम दे दूंगा। दिनेश जोशी ने इसे मान लिया और अपने पसंदीदा वाहन चालक रामनिवास को जो नीमरोट का अस्थायी वाहन चालक था, स्थायी करने को कहा। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस वाहन चालक से मिलकर दिनेश जोशी ने नीमरोट को सिरोही से अपने गांव जाते वक्त सिकन्दरा-दौसा के बीच १३ फरवरी, १९८७ को परिवहन निगम की बस से जीप भिड़वाकर मरवा दिया। दुर्घटना के वक्त जीप चालक रामनिवास था, जो साफ बच गया, जबकि नीमरोट की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। विधायकों का आरोप है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री के दबाव के कारण कोई कार्यवाही करने की बजाय हत्याकांड पर पर्दा डाल दिया। पत्र में कहा गया है कि नीमरोट की विधवा पत्नी ने अपने भतीजे के साथ बांसवाड़ा जाकर जब रुपए मांगे, तो पहले तो वह झांसा देते रहे, पर बाद में रुपए की एवज में उनके भतीजे को नौकरी लगाने की बात कही। इसके लिए श्रीमती नीमरोट तैयार नहीं हुईं। बताया जाता है कि श्रीमती कमला नीमरोट इस संदर्भ में जब मुख्यमंत्री जोशी से मिलीं, तो उन्होंने

रिश्वत व हत्या का आरोप: मुख्यमंत्री जोशी और उनके पुत्र दिनेश जोशी

साक्षात्कार/ **श्रीमती कमला नीमरोट**

'खून का बदला खून से लेना चाहती हूं'

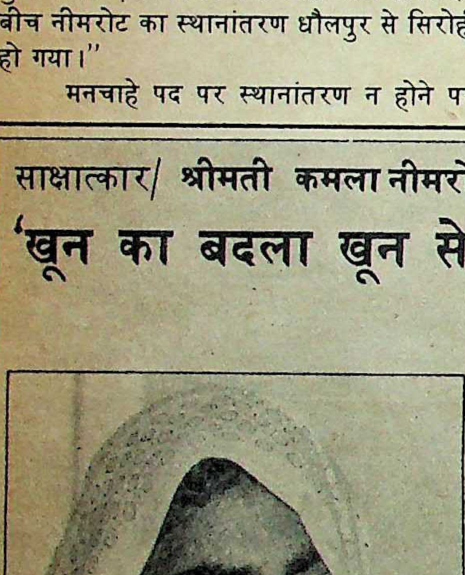

देहाती किस्म की ३५ वर्षीय श्रीमती कमला नीमरोट दस्तखत भर करना जानती हैं पर मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी के पुत्र श्री दिनेश जोशी के सम्बन्ध में उनके द्वारा जारी किया गया शपथ-पत्र पूरी सजगता से तैयार किया गया था। साक्षात्कार के समय बात समझ कर जवाब देने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं थी। उन्हें पैसे देकर पति द्वारा पोस्टिंग हासिल करना कतई अटपटा नहीं लग रहा था। प्रस्तुत हैं, कुछ सवालों के उनसे हासिल जवाब:

माया: आपका आरोप है कि दिनेश जोशी ने आपके पति से परिवहन अधिकारी जयपुर या आबकारी अधिकारी उदयपुर के पद पर लगवाने के नाम पर पैसे लिये? यह बात आपके सामने हुई?

श्रीमती नीमरोट: साब से हुई होगी। साब, मेरे सामने तो नहीं हुई।

माया: आपने शपथ-पत्र में पैसे का हिसाब लिखा है, यह पैसा नीमरोट साहब कहां से लाये?

श्रीमती नीमरोट: साब घर से लाये पैसा। साब ने मुझसे कहा कि जहां मैं हू, वहां तो मैं काम करूंगा नहीं। आप तो मुझे पैसे दो। मैंने पूछा, ऐसे पैसे कहां दोगे। तो बोलें भई मेरी दिनेश जोशी से यारी दोस्ती है और पवन कुमार से मैंने बात कर ली है। उनके हाथ की बात है और मैं तो आर०टी०ओ० जयपुर लगना चाहता हूं। चाहे पैसा कितना भी लग जाये। फिर पिताजी से कहा। पिताजी ने जमीन गिरवी रखकर पैसा लिया। पहले तीस हजार रुपए दिये जो साब ने बांसवाड़ा जाकर दिये। फिर बीस हजार और मांगे। पचास हजार रुपए देकर साब ने हमें बताया कि भई अब मैं आर०टी०ओ० जयपुर लग जाऊंगा। फिर सिरोही ट्रांसफर हुआ, तो साब बांसवाड़ा जाकर मिले, तो और पैसे मांगे। साब किसी से २० हजार रुपए लेकर गये और पवन कुमार रोकड़िया को देकर आये। बाद में यह रुपए जीप बेचकर वापस किये। फिर भी आर०टी०ओ० नहीं बने, तो पैसे वापस मांगे।

माया: आप भी नीमरोद साहब के साथ थीं?

श्रीमती नीमरोट: नहीं साब, मैं साथ नहीं गयी।

माया: पैसे आपके सामने मांगे?

श्रीमती नीमरोट: नहीं, साब बताते थे।

माया: आप यह कैसे कहती हैं कि जीप चालक रामनिवास नीमरोट साहब की मृत्यु के लिए जिम्मेवार हैं?

श्रीमती नीमरोट: तेरह तारीख (फरवरी, १९८७) को साब के बच्चे का लग्न था। साब रामनिवास के साथ दिनेश से मिले थे और कहा था मेरे बच्चे की शादी है, पैसे लौटा दो। पैसे तो दिये नहीं। रामनिवास उनका (दिनेश जोशी) आदमी है। उसने लौटते में जानबूझ कर यह काण्ड किया। हमको तो पूरा विश्वास है।

माया: आप नीमरोट साहब को 'साब' ही कहती हो?

श्रीमती नीमरोट: हां साब, मैं तो 'साब' ही कहती हूं।

माया: आपने रामनिवास को देखा है?

श्रीमती नीमरोट: एक-आध बार देखा है, पर मैं पहचानती नहीं। उसके कोई बच्चा नहीं है, औरत नहीं है। शैतान है। मैं तो साब से कहती थी कि ऐसा ड्राइवर क्यों रखते हो। वह तो उनका (दिनेश जोशी) आदमी है।

माया: नीमरोट साहब की मृत्यु के बाद आपने दिनेश जोशी से पैसे मांगे?

श्रीमती नीमरोट: हां साब, जब जान बूझकर एक्सिडेंट कर दिया। साब खत्म हो गये। दस बारह रोज तो हम चुप रहे। तीन रोज तो मुझे होश नहीं रहा। फिर मैंने सोचा, होना था जो तो हो गया, अब मेरे बच्चों को देखना है।

रुपए लौटाने का आश्वासन दिया। विधायकों ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री को अपदस्थ कर दोषी लोगों को सजा दिलाने की मांग की है।

संघर्ष समिति का गठन : राज्यपाल को पत्र लिखने के बाद भाजपा विधायक करोड़ीलाल मीणा विशेष सक्रिय हुए और उन्होंने 'कुलदीप नीमरोट हत्याकाण्ड जांच संघर्ष समिति' का गठन कर उसका दफ्तर अपने घर को बना दिया। अब यह समिति मीणा जाति के उन सारे नेताओं को कठोर पत्र लिख रही है जो मुख्यमंत्री श्री जोशी के साथ हैं। विशेष रूप से राज्य मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री मूलचन्द मीणा, विधायक भरतलाल मीणा को इन्होंने चेतावनी पत्र जारी किये हैं। इस समिति ने प्रधानमंत्री को केन्द्रीय कृषिराज्य मंत्री योगेन्द्र मकवाना के माध्यम से पत्र लिखा है। समिति ने १० अक्तूबर के अपने पत्र में वे सब आरोप दोहराये हैं जो भाजपा विधायक डा० करोड़ीलाल मीणा ने राज्यपाल को लिखे पत्र में दर्ज किये हैं।

इस मामले ने १६ अक्तूबर को नया मोड़ उस

असलियत उजागर करेंगे : भाजपा विधायक करोड़ीलाल मीणा और हरीश शर्मा

वक्त ले लिया, जब भाजपा विधायक डा० करोड़ीलाल मीणा ने अपने घर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उसमें श्रीमती कमला नीमरोट के साथ-साथ उन सब गवाहों को पेश किया, जिनके सामने अथवा साथ जाकर श्रीमती नीमरोट ने मुख्यमंत्री और उनके पुत्र से पैसे वापस मांगे थे। सारे प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता, जिससे यह कहा जा सके कि मृत अधिकारी नीमरोट ने मुख्यमंत्री के पुत्र दिनेश जोशी को रिश्वत के पैसे दिये थे। हां, यह जरूर साबित होता है कि मृत अधिकारी भ्रष्ट आचरण का अफसर था और इस वास्तविकता से अवगत था कि राज्य प्रशासन में रिश्वत देकर रिश्वत खाने की गुंजाइश-वाले पद हासिल किये जाते हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने माया को औपचारिक साक्षात्कार देने से तो मना कर दिया, पर यह जरूर माना कि प्रशासनिक अधिकारी नीमरोट की पत्नी श्रीमती कमला अपने भतीजे के साथ उनसे उनके पुत्र की शिकायत करने जरूर आयी थी। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में अपने पुत्र से बात की, तो उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर पैसे लेनें से इनकार किया। फिर इसमे भी कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री का पुत्र अगर रिश्वत ले ले, तो अधिकारी का काम होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संकट में फंसी हो, मुख्यमंत्री ऐसा कोई जोखिम नहीं उठायेंगे, जिनसे उनकी बदनामी हो। यह भी उल्लेखनीय है

मैंने अपने साथ साब के भतीजे रामदयाल को लिया और बांसवाड़ा गयी। मैं उससे (दिनेश जोशी) उसके घर पर मिली और बोली मेरे पैसे तो दो। आपनें करना था वो तो कर दिया। मेरा पति मैंने खो दिया, अब पैसे तो वापस दो। बोला कौन से पैसे? मैंने कहा साब, आर०टी०ओ० जयपुर लगने के लिए जो दिये थे वो दे दो आप। आपने रामनिवास से टक्कर दिलवाकर मेरे पति को तो खत्म कर दिया।

माया : दिनेश जोशी का क्या जवाब था?

श्रीमती नीमरोट : कहने लगा आपका कोई काम हो तो मैं करने को तैयार हूं। आपके बच्चे की नौकरी लगवा दूंगा। पेंशन दिलवा दूंगा। मैंने कहा, सरकार में तो नियम है, पेंशन बंधेगी तो बंध जायेगी। मेरे बच्चे की नौकरी मैं लगवा लूंगी, अभी तो वो पढ़ रहा है। मैं तो मेरा पैसा लेना चाहती हूं। तो बोला, मैं आ रहा हूं जयपुर और जयपुर में पैसे दे दूंगा। हम जयपुर लौट आये और यहां आकर मैं अपने भतीजे अमरसिंह के साथ मुख्यमंत्री के घर गयी, पर वह तो आया ही नहीं। मेरा भतीजा चक्कर काटंता रहा। मैं घर लौट गयी। जब काफी समय बीत गया, तो अपने भतीजे के साथ मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के पास गयी।

माया : मुख्यमंत्री से आप कहां पर और कब मिलीं?

श्रीमती नीमरोट : सिविल लाइन में मिली। लिखी-पढ़ी तो मैं हूं नहीं। सब बातें लिख कर ले गयी थी। हमें अन्दर बुलाया और बोले भई चार रोज बाद आ जाना। अभी तो मैं जल्दी में हूं। दिल्ली जा रहा हूं। चार रोज बाद में गये, तो बोले भई पैसे तो देने ही हैं। आप तो जाओ, अपने भतीजे (अमरसिंह) को भेज देना मैं पैसे दे दूंगा। पर दिये आज तक नहीं।

माया : मुख्यमंत्री ने कभी पैसे देने के लिए इनकार नहीं किया?

श्रीमती नीमरोट : नहीं कभी-नहीं किया।

माया : विधान सभा में चर्चा के बाद क्या हुआ?

श्रीमती नीमरोट : हमारे रिश्तेदार और जान-पहचानवाले आ रहे हैं और कह रहे हैं भई पैसे मिल जायेंगे, पर चुप रहो। पर मैंने कहा, अब मैं पैसे लेनेवाली नहीं। अब तो मैं सबको बताऊंगी। जब मैं चक्कर लगा रही थी, तो किसी ने नहीं कहा, पैसे ले लो। आज तक मेरी पेंशन नहीं बनी। तब यह रिश्तेदार नहीं, अब आ रहे हैं। बस मेरे एक बच्चे को बाबू लगा दिया। इतने बड़े अफसर के बच्चे को बाबू बनाया है। मैं खेती करके ही पेट पाल लूंगी। अब यह कहते हैं कि मैं क्या चाहती हूं? मैं कहती हूं कि मैं खून का बदला खून से लेना चाहती हूं। मेरा समधी भी आया। उसने ६१ हजार से मेरे बच्चे को रोका है (यानी टीका दिया है) वह भी पैसे लेने की बात कह रहा था। उसके दो औरत है। मैंने कहा जरा एक औरत को तो मार दीजिये पैसे के लिए। मेरा आदमी खत्म हो गया और अब आप लोग पैसा लेने की बात कह रहे हैं।

माया : शपथ-पत्र आपसे किसने लिखवाया?

श्रीमती नीमरोट : किसी ने नहीं। मैं साब के साथ रही हूं। फिर खाना भी खाती हूं। थोड़ी-बहुत समझ मुझमें भी है।

माया : डा० करोड़ीलाल का कोई सहयोग रहा?

श्रीमती नीमरोट : साब इनसे तो मेरी मुलाकात ही अभी हुई है। मैं इनके पास आयी। मैंने समझा मीणे तो सारे मर गये उनके (नीमरोट) यार-दोस्त भी मर गये-औरों को ही टटोलूं। इस पर एम०एल०ए० (करोड़ीलाल) साब ने मदद की।

माया : नीमरोट साहब की पहले भी पोस्टिंग पैसे देने से होती रही थी, क्या?

श्रीमती नीमरोट : साब पहले तो नहीं दिये।

माया : यह पहला मौका था?

श्रीमती नीमरोट : हां, पहला ही था।

माया : जयपुर के आर०टी०ओ० क्यों बनना चाहते थे, नीमरोट साहब?

श्रीमती नीमरोट : क्या पता साब। बनना तो चाहते ही थे। सब अच्छी जगह ही जाना चाहते हैं।

माया : क्या वह जानते थे कि यह पद एक लाख रुपए में मिलता है?

श्रीमती नीमरोट : हां साब। सब यार-दोस्त तो बन ही गये थे। यह करवा भी सकते थे, इसीलिए पैसे दिये।

माया : क्या पैसे देते वक्त नीमरोट साहब के साथ कोई था?

श्रीमती नीमरोट : टोडाभीम का रहनेवाला पृथ्वीराज मीणा साथ था। यह बांसवाड़ा में टेलीफोन आपरेटर है। अब पता नहीं हां कहेगा या नहीं।

श्रीमती कमला नीमरोट के बयान का उनके भतीजे अमरसिंह ने समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उसे भी नौकरी का लालच देने की बात माया को कही है। श्रीमती नीमरोट के साथ बांसवाड़ा जानेवाले राम दयाल मीणा भी इस बात का समर्थन करते हैं कि दिनेश जोशी ने उनकी उपस्थिति में पैसे की जगह और सहायता व सहयोग देने की बात कही।

—ओम सैनी

कि मुख्यमंत्री का पुत्र अपने बलबूते पर पूर्व में बांसवाड़ा नगरपालिका का अध्यक्ष बना है और राजनीति की साजिशों से वाकिफ है।

कुछ सवाल: फिर भी सारे प्रकरण में कुछ सवाल ऐसे पैदा होते हैं जिनसे दाल में काला नजर आता है। मसलन, मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के खिलाफ चले कथित चरित्रहनन पर इन पंक्तियों के लिखे जाने तक विधान सभा में मुंह क्यों नहीं खोला? विपक्ष के विभिन्न बड़े नेताओं ने इस मामले में खामोशी क्यों धारण कर रखी है? स्वयं विधायक डा० करोड़ीलाल मीणा अपने साथी विधायक हरीश शर्मा के साथ चुप्पी क्यों साध गये?

दरअसल, डा० करोड़ीलाल मीणा इस वर्ष जनवरी माह में उस वक्त चर्चा का विषय बने थे, जब उनके निर्वाचन क्षेत्र महुवा के पास गंगापुर सिटी में मीणा समुदाय और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के बीच दंगा हो गया था। दंगे की वजह मुस्लिम समुदाय के कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा दूसरे समुदाय की लड़कियों से छेड़छाड़ करना था और जब मीणा समुदाय के छात्रों ने ललकारा, तो उन्होंने चाकू मारकर सात छात्रों को घायल कर दिया था। घायलों में एक छात्र कैलाश मीणा की बाद में मृत्यु हो गयी थी। इस वारदात के बाद जो आन्दोलन हुआ, उसके नेता विधायक डा० करोड़ीलाल मीणा बने। प्रशासन द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में इनकी रिहाई के लिए इनके दल से ज्यादा मीणा युवक गोलबन्द हुए। राजस्थान आदिवासी मीणा छात्र संघ का गठन हुआ, जिसका तालमेल अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र संघ से हो गया। तब से विधायक डा० करोड़ीलाल मीणा अपने समुदाय को अनुसूचित जाति समूहों के साथ जोड़कर एक प्रभावी दबाव समूह बनाने की योजना में सक्रिय हैं।

मुख्यमंत्री ने लालच दिया: श्रीमती कमला नीमरोट का भतीजा अमरसिंह और घटना का गवाह रामदयाल

मृत प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप नीमरोट द्वारा रिश्वत देने के मामले में वह कहीं भी उन्हें भ्रष्ट आचरण का करार नहीं देते, हां यह जरूर कहते हैं कि मुख्यमंत्री और उनका पुत्र भ्रष्ट है।

उधर मुख्यमंत्री के पुत्र दिनेश जोशी ने विधायक करोड़ीलाल मीणा के संवाददादा सम्मेलन आयोजित करने के चार रोज बाद यानी २० अक्तूबर को बांसवाड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तीन विधायकों सहित सात व्यक्तियों पर मानहानि का दावा दायर किया। दावे में आरोप लगाया गया है कि उक्त लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक समाचार पत्रों के माध्यम से उन पर नीमरोट की हत्या करवाने का झूठा आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचायी है। दिनेश जोशी वर्तमान में राजस्थान स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी बैंक बांसवाड़ा के अध्यक्ष भी हैं।

बहरहाल, रिश्वत लेने और काम न होने पर रिश्वत के पैसे वापस करने के बजाय उस व्यक्ति की ही हत्या करवा देने का यह दूसरा मामला है, जिसमें मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के पुत्र दिनेश जोशी का नाम सुर्खरू हो रहा है। सर्वाधिक बदनामी खुद मुख्यमंत्री जोशी की हो रही है। इस मामले की पूरी जांच करवाकर दोषी व्यक्ति को दंडित करने में श्री जोशी जितना विलंब करेंगे, वह उनकी छवि के लिए उतना ही घातक सिद्ध होगा—क्योंकि आरोप अब उन्हीं पर लगने लगा है कि वह खुद भी अपने पुत्र के कथित भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

—ओम सैनी

साक्षात्कार/**करोड़ीलाल मीणा**
भाजपा विधायक

‘हम इस षड्यंत्र का खुलासा करके रहेंगे’

राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक करोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के पुत्र दिनेश जोशी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कुलदीप नीमरोट की हत्या का मामला उठाया था। ‘माया’ से इस संबंध में उन्होंने खुलकर बातचीत की है। प्रस्तुत हैं, इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश:

माया: विधान सभा सत्र में आपने मुख्यमंत्री के पुत्र दिनेश जोशी पर पैसे लेकर पोस्टिंग करवाने और पैसे वापस मांगने पर हत्या करवाने का आरोप किन दस्तावेजों के आधार पर लगाया है?

मीणा: मुझे श्रीमती कमला नीमरोट अपने भतीजे अमरसिंह के साथ मिली और सारा किस्सा बताया। मेरी मदद चाही। हिन्डोन में मेरी मुलाकात हुई। वैसे, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आती। मैं किसी काम से गया था, तो यह लोग मिलने आये। मैंने जब पैसे देने के बारे में पूछा तो जमीन गिरवी रखने के कागज और जीप बेचने के दस्तावेज मुझे दिखाये। इन्हें देखने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि आरोप में सच्चाई है। जो लोग इस प्रकरण से वाकिफ थे, उनसे भी मिला। मैंने श्रीमती नीमरोट से सारा मामला लिखवाया और विधान सभा में पेश करने का आश्वासन दिया। विधान सभा में सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री के घोड़े दौड़ने लगे। मंत्री मूलचंद मीणा, विधायक भरतलाल इत्यादि श्रीमती नीमरोट के पास गये। ७० हजार रुपए देने की बात कही। यह भी कहा कि तुम मुख्यमंत्री से टक्कर नहीं ले सकती। यह लोग मुझे भी मुख्यमंत्री से ले जाकर मिलाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। बहरहाल, दो अक्तूबर को मैं मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने मेरा हाल पूछा और बोले, “भई मेरी भैरोंसिह जी (विपक्ष नेता) से बात हुई थी, उन्होंने कहा इसकी तबीयत खराब रहती है, इसे अमेरिका भेज दो। मैंने आपको तुरन्त भेज दिया और आप हो आये, अब क्या हाल है? इसके बाद मुख्यमंत्री बोले, “एम०एल०ए० साहब आपको मैं एक बात बताऊं, मैं सुबह देवी की पूजा करता हूं। ईश्वर में विश्वास रखता हूं। यह मामला जो आपने विधान सभा में उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं देवी की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने बेटे को यहां बुलाया था। उसने मेरे पोते के सर पर हाथ रखकर कहा था कि पिताजी यह काम मैंने नहीं किया। इसलिए एम०एल०ए० साहब इस बात को मैं सत्य नहीं मानता। फिर भी आप कहें, तो मैं श्रीमती कुलदीप नीमरोट के पैर पकड़ लूं। माफी मांग लूं।” मुख्यमंत्री ने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे यह कहा। मैंने कहा कि जब उसने कुछ किया ही नहीं है, तो पैर पकड़ने की क्या जरूरत है और फिर मुझे बुलाया ही क्यों है? मुख्यमंत्री बोले, ‘भई आपका कोई काम हो। विकास का काम हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं।’ मैंने कहा, ‘मैंने विधान सभा में यह सवाल इसलिए नहीं उठाया है कि इसके बदले में मैं कुछ ले लूं। जिस तरह से आपका बेटा कह रहा है कि पैसे नहीं लिये, उसी तरह वह औरत (श्रीमती नीमरोट) भी भगवान के मन्दिर में गंगा जल उठाकर कहती है कि पैसे दिये हैं और मेरे पति की हत्या करवायी गयी है। आप इसकी जांच करवा लें। बाद में इस मुलाकात के सम्बन्ध में मैंने अपने नेता श्री भैरोंसिह शेखावत को अवगत कराया।’

माया: श्री शेखावत ने इस सम्बन्ध में क्या कहा?

मीणा: उन्होंने कहा, यह बात तो सही है कि उससे पैसे लिये, पर इसे इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा कि यह हत्या हुई है या दुर्घटना। मैंने अपने दल के पदाधिकारियों को सारे मामले से अवगत कराया है और अब हम इस षड्यन्त्र का खुलासा करके रहेंगे।

—ओम सैनी

छाया: गोपाल संगर

सर्वाधिक आत्महत्याएं जापान में

आत्महत्या भारत में ही नहीं प्रायः दुनिया भर के सभी मुल्कों में एक दण्डनीय अपराध है। प्रायः हर आत्महत्या के पीछे निराशा और असफलता से उत्पन्न अनिश्चित भविष्य का भय प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन जापानियों द्वारा की गयी आत्महत्याओं के पीछे उनकी खुद्दारी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और सबसे अधिक आत्महत्याएं जापान में होती हैं।

गत वर्ष जापान की बडी व्यावसायिक कम्पनियों के २७५ डायरेक्टरों ने महज इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके डायरेक्टर पद पर रहते हुए उनकी कम्पनी को नुकसान पहुंचा था, भले ही वे स्वयं इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। न केवल कम्पनियों के डायरेक्टर, बल्कि आत्महत्या करनेवालों में सांसद, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न सरकारी संस्थानों के प्रमुख भी शामिल हैं, जिन्होंने किसी-न-किसी गडबडी या असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए आत्महत्या कर ली। बड़े लोगों द्वारा खुदकशी का गत वर्ष आलम यह था कि प्रति सप्ताह जापान में ६ बड़े लोगों ने आत्महत्या की। यह खुद्दारी वहां बड़े लोगों की ही बपौती नहीं है, बल्कि एक यूनियन नेता ने तो सिर्फ इसीलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि कोयले की एक खदान को बंद करने से रोकने के लिए उसने जो आंदोलन चलाया, वह असफल हो गया था।

जापानी सरकार चिंतित है। लेकिन इन आत्महत्याओं को रोक पाना किसी के भी बस का नहीं है क्योंकि इसे वहां के समाज में खुद्दारी का लक्षण माना जाता है और कहा जाता है कि जिम्मेदारी की यही भावना जापान की प्रगति का रहस्य है।

बन्दरों की मिल्कियत

जर (धन), जोरू (पत्नी) और जमीन-इन तीनों को झगड़े का प्रमुख कारण माना जाता रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर नजारा कुछ दूसरा ही था। पिछले मास करीब ढाई सौ बन्दरों ने एक छोटी नदी के इस और उस पार के सैकड़ों ग्रामवासियों को एक दूसरे से लड़नें-मरने के लिए हथियारों के साथ मोर्चा लगाने पर मजबूर कर दिया। गोण्डा जिले में वजीरगंज एक छोटी नदी के पूर्वी क्षेत्र और तरबगंज पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वजीरगंज के नौबस्ता गांव में अचानक करीब ढाई सौ बन्दर जाने कहां से आ गये, उन्होंने फसल को नुकसान पहुंचाना और गांव में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, तो गांव के बुजुर्गों ने सलाह-मशविरा किया कि किसी तरह इन बन्दरों को नदी के उस पार उतार दिया जाये, तो इनका उत्पात समाप्त हो सकता है। बस फिर क्या था—गांव के उत्साही युवकों ने नदी पर बांस का एक पुल बनाया और किसी तरह बन्दरों की धर-पकड़ की, कुछ को हांक लगाई और उस पुल से उन सबको तरबगंज की ओर उतार दिया और पुल तोड़ दिया। इन बन्दरों ने तरबगंज पहुंचकर ऐसा उत्पात मचाया कि उस गांव के बुजुर्गों ने भी वैसा ही निर्णय लिया। नदी पर बांस का पुल बनाया और करीब सौ बन्दरों को पकड़कर किसी तरह पुल से वजीरगंज की ओर खदेड़ दिया। बन्दरों के उत्पात से पहले से परेशान वजीरगंज क्षेत्र के ग्रामीणों का धैर्य टूट गया और वे हथियार लेकर नदी के किनारे जमा हो गये और बन्दरों को उस पार खदेड़ने लगे, इसी तरह हथियार लेकर तरबगंज के ग्रामीण भी नदी के उस किनारे जमा हो गये और बन्दरों को इस पार भेजने लगे। गोलियां चल जातीं, अनेक लोग मर जाते, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गयी। तरबगंज के ग्रामीणों का कहना है कि बन्दरों को इस ओर क्यों खदेड़ा गया—हम उन्हें वहीं पहुंचा कर रहेंगे जहां से वे खदेड़े गये हैं। दूसरी ओर वजीरगंज के ग्रामीणों का कहना था कि क्या बन्दरों ने हमारे क्षेत्र की जमीन का बैनामा करा लिया है।

बहरहाल, पुलिस झगड़े को निपटा नहीं सकी, दोनों पक्षों में अनेक दिनों तक मोर्चेबंदी चली। बन्दर इधर से उधर खदेड़े जाते रहे। पता चला कि खदेड़े जाने से परेशान होकर बन्दर स्वयमेव वह इलाका छोड़कर चले गये और एक बड़ा खून-खराबा होने से बच गया।

14 दिनों का घर में ही मुफ्त आजमाइशी ऑफर!

नया सौना सिस्टम 900

आसान, आजमाया हुआ—असरकारक तरीका कमर का नाप कई इंच कम करे, वजन घटाने में मदद करे, बिना कड़ी वर्जिशों के.

जल्दी कीजिए! नीचे दिया हुआ मुफ्त आजमाइशी कूपन आज ही भेज दीजिए और सौना सिस्टम—900 आजमाइये कैसे गायब होता है पेट का थुलथुलापन और कैसे सुडौल दिखते कूल्हे सौना सिस्टम—900 फालतू पानी निकालकर और थुलथुलापन घटाकर आपकी कमर से कई इंच फालतू चर्बी निकाल देता है और कुछ आसान सी वर्जिशों के बाद आपके खड़े होने का अंदाज निखर जाता है, आपका आत्मविश्वास छलकने लगता है और आप पहले से कही ज्यादा छरहरे नजर आते हैं—बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहते थे!

इस्तेमाल करने के तरीके के सचित्र ब्यौरे सहित

तसल्ली की गारंटी वरना पैसे वापस!

सौना सिस्टम—900 सिर्फ १४ दिनों तक आजमाइये. अगर इस आजमाइशी अवधि के दौरान आप नतीजों से पूर्णतया संतुष्ट न हों, तो सारी सामग्री हमें लौटा दीजिए और पैसे (डाक व प्रेषण खर्च घटाकर) वापस ले लीजिए. कोई सवाल जवाब नही.

पैसे बचाइये!
हजारों रु.238/- में बेचे जा चुके हैं!
अब सिर्फ रु.196/- में रु.42/- की बचत

तीन क्रमवार वर्जिशें, कितनी आसान... अ.ब.क.

अ सौना सिस्टम- 900 से चित्र मे दिखाई गई आसान सी वर्जिश कीजिए दिन मे सिर्फ कुछ मिनट

ब सौना सिस्टम- 900 को करीब 20 मिनट तक पहने. रखिये ऐसा करते समय आप आराम करे

क सौना सिस्टम- 900 उतार दीजिए आप अपनी कमर को पहले से मजबूत, सपाट और कसी हुई महसूस करेंगे.

ABHA

कृपया नोट करें सभी वी पी पी आर्डरों के लिए वी पी पी भुगतान सीधे पोस्ट ऑफिस को देय होगा

खेल सामग्री की सभी प्रमुख दुकानों मे उपलब्ध वी पी पी द्वारा उपलब्ध बुलवर्कर मेहता महल. 15 मैथ्यू रोड बम्बई 400 004.

यह कूपन आज ही भेजिए

MY-57

बुलवर्कर प्रा.लि., मेहता महल. 15. मैथ्यू रोड. बंबई 400 004.

कृपया मुझे **सौना सिस्टम- 900** घर मे ही **14 दिनों की मुफ्त आजमाइश** के लिए भेज दीजिए अगर मैं इसके नतीजों से पूर्णतया संतुष्ट नही हुआ तो आजमाइशी अवधि पूरी होने के पहले ही मै सारी चीजें वापस लौटा दूंगा और अपना पैसा (डाक व प्रेषण खर्च घटाकर) वापस ले लूंगा. कोई सवाल-जवाब नही किये जायेंगे.

कृपया उचित चौकोर में ☑ सही का निशान लगायें

☐ रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से भेजें. मै रु. 196 - का ड्राफ्ट/भा.पो.आ./मनी ऑ. नं. ....
ता.................... से भेज रहा हूं. (बुलवर्कर प्रा.लि. को देय).
☐ वी.पी.पी. से भेजें. डिलीवरी मिलने पर मै डाकिये को रु. 196.- देने का वादा करता हूं.

नाम: ....
पता: ....
....
पिन .... हस्ताक्षर SS-702-LO

कुछ तुम्हारी कुछ हमारी पसन्द है लाजवाब

चुटकी पान मसाला खाईऐ जनाब

सौंफ इलायची छुआरे वाला

चुटकी

पान मसाला

Chutki
"A Perfect Mouth Freshner"

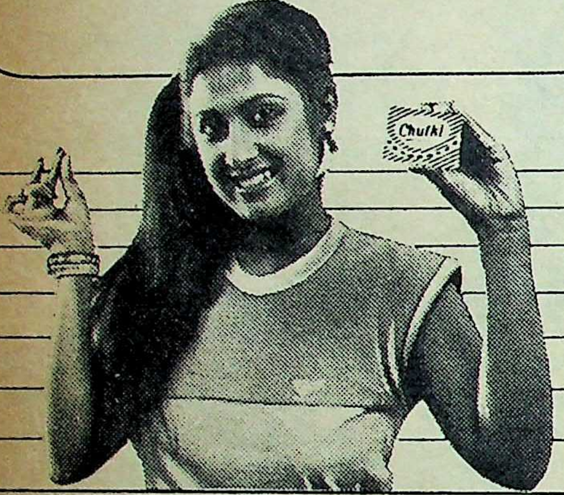

CHUTKI
चुटकी
چٹکی
சுட்கி
চুটকী
ਚੁਟਕੀ
ચુટકી

उम्र भी कुछ कम नहीं, फिर भी

कैसा तन्दुरुस्त, कैसा फुर्तीला

ये सब है **ओकासा** की बदौलत
शक्ति के साथ-साथ
काम की लगन भी.

एक अनोखा ज़ोरदार फार्मूला जो किसी अन्य टॉनिक में नहीं. बिरली जड़ी बूटियों का सत्त. साथ ही १८ बायोकेमिकल्स, विटामिन और खनिज भी. औषधी के रूप में जाना माना, जिसकी दुनिया भर में धाक है. हर दिन के भरपूर आनन्द के लिए अनोखा ज़रिया –**ओकासा**

दवाओं की सभी प्रमुख दुकानों में

ओकासा

ओकासा की मुफ़्त पुस्तिका के लिये लिखिये:
OKASA CO. PVT. LTD. 12, Gunbow Street, Bombay 400 001.

SILVER FOR MEN - 50 TABLETS
OKASA
जाना-माना
शक्तिदायक
ओकासा
२५ दिनों के लिये असरदार
५० गोलियों के सुविधाजनक पैक में

पांडातराई

हरिजनोद्धार के नाम पर जातीय संघर्ष

राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर में हरिजनों का घोषणापूर्वक प्रवेश कराने के चक्कर में रायपुर के सर्वोदय सांसद केयूर भूषण की ऐसी पिटाई हुई थी कि वह मरते-मरते बचे थे, और वहां घोर जातीय उपद्रव की स्थिति पैदा हो गयी थी। इससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और इस २४ अक्तूबर को वह मध्य प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के साथ हरिजनों का महामाया मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जा पहुंचे, बिलासपुर जिले के पांडातराई गांव में। यहां भी उन्हें न केवल प्राणों के लाले पड़ गये, बल्कि इन दोनों नेताओं को उपद्रवी भीड़ से बचाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें पांच लोग मारे गये। अब वहां जातीय तनाव उग्र हो रहा है। नाथद्वारा और महामाया—इन दोनों मंदिरों में हरिजन पहले से ही जाते रहे हैं, फिर ये नेता बिना बात हरिजन-प्रवेश का बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या हरिजन वोट बटोरने के लिए जातीय उपद्रव भड़काने के सिवा अब इन नेताओं को कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आता?

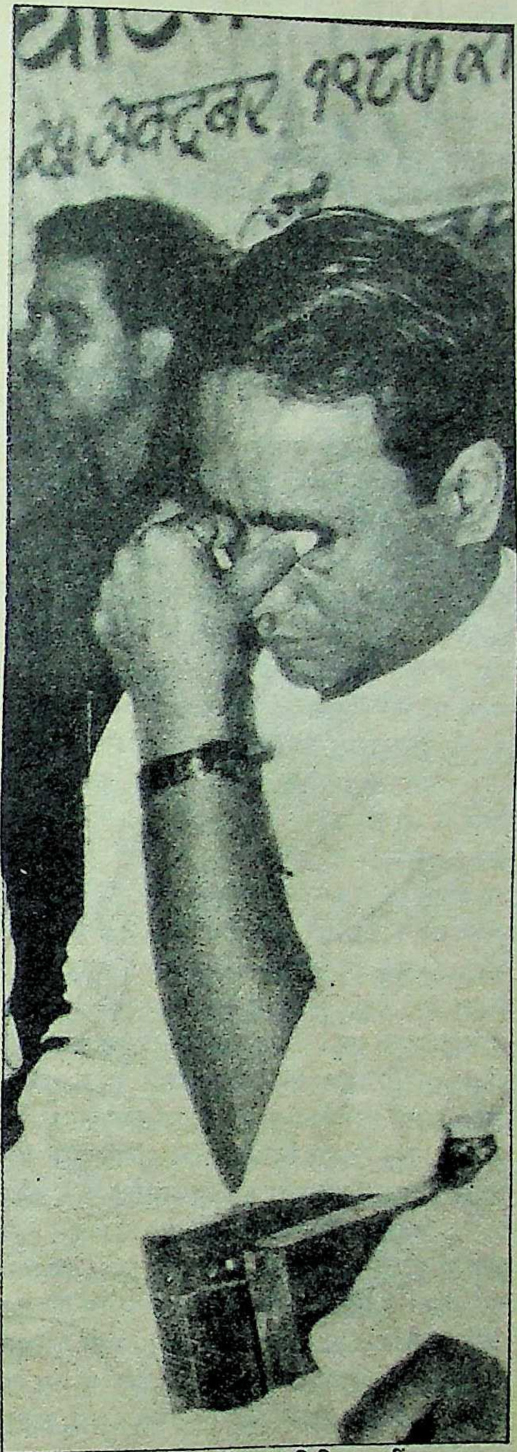

जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण था: दिग्विजय सिंह

बिलासपुर जिले में मुंगेली से ४२ कि०मी० और पंडरिया से कवर्धा रोड पर करीब दस कि०मी० की दूरी पर स्थित है, पांडातराई ग्राम। लगभग चार हजार की आबादी का यह गांव सवर्णबहुल है। सवर्ण हरिजनों के मुकाबले संपन्न हैं और शक्तिशाली भी। गांव में महामाया का लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना एक मंदिर केदारपुरी गोस्वामी की १.२७ एकड़ भूमि में से दो डिस्मिल जमीन पर स्थित है। हालांकि, यह मंदिर निजी संपत्ति है, लेकिन यह किसी रिहायशी मकान के हिस्से या किसी अहाते में स्थित न होकर खुले में स्थित है और गांव के सामान्यजन, सवर्ण और हरिजन, मंदिर में पूजार्चन के लिये बेरोकटोक जाते रहे हैं। करीब १० वर्ष पूर्व अर्जुन गुप्ता ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। क्षेत्र के इंका सांसद खेलनराम जांगड़े का कहना है कि वह स्वयं इस मंदिर में कई बार हो आये हैं और उन्हें कभी किसी ने मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका। फिर क्या कारण है कि मंदिर में हरिजन प्रवेश को लेकर ज्योतिपर्व दीपावली के दो दिन बाद पांडातराई में पुलिस को गोली चलानी पड़ गयी, जिससे चार लोग वहीं तत्काल मारे गये तथा २० अन्य घायल हो गये और वहां अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ गया?

पिछले संदर्भ: संदर्भों को देखें, तो जिले के इतिहास में जातीय टकराव की यह घटना पहली कतई नहीं है। सन् १९६९ में मुंगेली तहसील में ही गुरुवाइन डबरी में हरिजन-सवर्ण संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में तीस हरिजनों की मृत्यु हुई थी और इसकी तीखी अनुगूंज ने तत्कालीन सांसद (स्व०) मिनीमाता और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह को गुरुवाइन डबरी आने को बाध्य कर दिया था। आर्थिक और सामाजिक विषमता के बावजूद पांडातराई में पिछले साल तक सब कुछ ठीकठाक चल रहा था, लेकिन इस वर्ष कुछ घटनाएं ऐसी हुईं कि हालात शनैः शनैः बिगड़ते गये। इस साल के शुरू में क्षेत्र के यादवों (अहीर या राउत) की यह मनःस्थिति बनती गयी कि वे सवर्णों के जूठे बर्तन साफ करने का काम नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि पानी भरने और बर्तन भांडे साफ करने का काम प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के तहत सदियों से राउत करते आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक जागृति और शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने उन्हें प्रेरित किया कि इस काम को तिलांजलि दे दी जाये। अहीरों का यह निश्चय, अनेक कारणों से सवर्णों को नागवार गुजरा और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का मन-ही-मन फैसला कर डाला। अनेक जगहों पर सवर्णों के नाइयों ने यादवों की दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। मार्च की बात है कि पांडातराई गांव का हरिजन उपसरपंच नाई के यहां दाढ़ी बनवाने गया, तो वहां खड़े कुछ सवर्ण युवकों ने उसका उपहास उड़ाया और नाई को दाढ़ी बनाने से रोका। इसी प्रकार होटलों में जूठे बर्तन साफ करने से इंकार से मनोमालिन्य बढ़ा। इन्हीं दिनों सवर्णों में संकीर्णता और कट्टरता ने जोर मारा और उन्होंने फैसला कर डाला कि मंदिर में अब हरिजनों को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। और-तो-और, सवर्णों के खेतों पर हरिजनों को काम मिलना भी बंद जैसा हो गया। बहिष्कार और आर्थिक नाकेबंदी की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। मार्च में संभागायुक्त मनोज कुमार जब पांडातराई गये तो, बताते हैं कि एक

सवर्ण शिक्षक ने यहां तक कहा कि वह हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि हरिजनों के शरीर से दुर्गंध आती है। अधिकारियों के दौरों के बाद भी जब स्थिति में विशेष फर्क नहीं आया, तो हरिजनों ने सामूहिक भूख-हड़ताल का सिलसिला प्रारंभ किया। यह क्रम काफी दिनों तक चला और अंततः रायपुर के सर्वोदयी सांसद केयूर भूषण के समझाने पर ही टूटा।

सम्मेलन से उत्तेजना: १७ अक्टूबर को मुंगेली में अखिल भारतीय खेत मजदूर परिषद और हरिजन सेवक संघ का सम्मेलन था। इसके पूर्व करीब डेढ़ सौ हरिजनों ने दो दिन में ४२ कि०मी० की पदयात्रा की और १६ अक्टूबर की रात को वे सांसद जांगड़े के मुंगेली स्थित आवास पर पहुंचे। १७ अक्टूबर को सम्मेलन हुआ और इसमें कुछ ऐसी बातें कही गयीं, जिन्होंने जाने अनजाने जातीय तनाव की मद्धिम आग में घी डालने का काम किया। इस सम्मेलन में सांसद जांगड़े, पूर्वविधायक बैजनाथ चंद्राकर झीनाभाई दरजी, सांसद केयूर भूषण, सुश्री निर्मला देशपांडे आदि ने भाग लिया और अध्यक्षता की प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह ने। अपने अध्यक्षीय भाषण में दिग्विजय सिंह ने मंदिर में हरिजन प्रवेश के मसले का उल्लेख किया और कहा कि अगर आगामी १४ नवंबर तक मामला नहीं सुलझा तो वह चौदह नवम्बर को पांडातराई आयेंगे और मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करायेंगे।

बताते हैं कि कुछ हिंदुओं ने तैश में यहां तक कहा कि केयूर नाथद्वारा से तो बचकर आ गये, मगर यहां से सही सलामत लौट नहीं सकेंगे। यह बात सच हो या गलत, मगर यह सच है कि अगर केयूर क्षेत्रीय सांसद जांगड़े की बात मानते और विवेक से काम लेते, तो अनहोनी टल सकती थी।

दिग्विजय सिंह का यह कहना था कि विवाद और तेजी से भड़क उठा। विवाद के तूल पकड़ने की खबर नेताओं और अधिकारियों तक पहुंची। २३ अक्टूबर को खेलनराम जांगड़े और बैजनाथ चंद्राकर पांडातराई पहुंचे। जांगड़े व चंद्राकर ने 'माया' को बताया, "हम लोगों के साथ में इंका कार्यकर्ता भी थे। हमने दोनों पक्षों से बातचीत कर कोशिश की कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाये, ताकि जातीय सौहार्द बना रहे और हम इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। हम दोनों सवर्णों के साथ मंदिर में भी गये। सवर्ण इस पर सहमत भी हो गये थे कि मंदिर में प्रवेश के मामले में मार्च के पूर्व की स्थिति बहाल कर दी जाये।" दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि अगले दिन केयूर भूषण के आगमन की सूचना से सवर्णों में क्षोभ और उत्तेजना फैली और उनका कहना था कि केयूर को यहां आने की क्या जरूरत है और वह किस प्रयोजन से आ रहे हैं? बताते हैं कि कुछ हिंदुओं ने तैश में यहां तक कहा कि केयूर नाथद्वारा से तो बचकर आ गये, मगर यहां से सही सलामत लौट नहीं सकेंगे। यह बात सच हो या गलत, मगर यह सच है कि यदि केयूर क्षेत्रीय सांसद जांगड़े की बात मानते और विवेक व दूरदर्शिता से काम लेते, तो अनहोनी टल सकती थी। सांसद जांगड़े के अनुसार, "चार-पांच दिनों बाद पुनः आने की बात कहकर और दोनों पक्षों को समझाबुझाकर २३ तारीख की रात को हम दोनों (वह व चंद्राकर) लौट आये थे। उस दिन कलेक्टर व एस०पी० भी पंडरिया में थे। सुबह पांडातराई जाने के पूर्व सबेरे नौ बजे और रात में करीब साढ़े नौ बजे मैंने फोन पर केयूर भूषण से बातचीत की। बातचीत के बाद मैं आश्वस्त था कि वह पांडातराई नहीं आयेंगे। वैसे भी उन्हें २४ अक्टूबर को भोपाल जाना था, मैंने प्रशासन से भी कहा कि केयूर भूषण जी को पांडातराई आने से मना कर दिया जाये।"

घटनाक्रम: इन तमाम बातों के बावजूद केयूर भूषण बगैर किसी को खबर किये सीधे निजी वाहन एमपीटी १२० से मुंगेली होते हुए पांडातराई पहुंच गये। २४ अक्टूबर को वहां हाट का दिन होने के कारण काफी भीड़भाड़ थी। केयूर के वहां पहुंचने और परिचय देने की देर थी कि लोगों ने उन्हें घेर लिया और केयूर भूषण व दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। उत्तेजना के माहौल में थोड़ी देर बाद मारपीट शुरू हो गयी, जिसमें केयूर भूषण, उनके साथी रामनिहाल व ड्राइवर कृष्णकुमार को चोटें आयीं। स्थिति बिगड़ती देख पुलिसवाले उन्हें घेरे में लेकर समीपवर्ती वन-विश्रामगृह में ले गये।

कहा जाता है कि एक पुलिसकर्मी ने इस बीच हवा में गोली दागी मगर भीड़ छंटी नहीं। प्रशासन का कहना है कि अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस की एक जीप में आग लगा दी और बेकाबू हो गयी, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने गोलीचालन का आदेश दे दिया। इसके विपरीत ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने बगैर चेतावनी के गोली चलाई और गोलियां चलाने के बाद औचित्य सिद्ध करने के लिए खुद जीप में आग लगा दी। कलेक्टर उदय वर्मा के अनुसार पुलिस ने सोलह राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें तीन राउंड हवाई फायर सम्मिलित हैं। बहरहाल, पुलिस की गोली से कृष्णकुमार गुप्त (२७ वर्ष), सीताराम गुप्ता (४२ वर्ष), रामगुलाम तिवारी (४५ वर्ष) और शिवचरण जायसवाल (२६ वर्ष) घटनास्थल पर ही मारे गये। केयूर भूषण अपरान्ह करीब सवा तीन बजे पांडातराई पहुंचे थे और वहां सूरज डूबने के कुछ देर बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देना पड़ा। इस बीच खबर लगी कि एक और ग्रामीण भैयालाल तिवारी (५५ वर्ष) की भी गोलीकांड में मृत्यु हो गयी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। घटना के बाद अनेक ग्रामीणों ने केयूर भूषण को दोषी ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। गोलीकांड की खबर जब भोपाल पहुंची, तो मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने उसकी जांच के आदेश दे दिये और २५ अक्टूबर को गृहराज्य मंत्री कै० जयपाल सिंह, शिक्षाराज्य मंत्री चित्रकांत जायसवाल, गृहसचिव विनय शंकर, पुलिस-महानिदेशक एम० नटराजन और पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तचर) नरेंद्र सिंह पांडातराई पहुंचे। संपूर्ण घटनाक्रम ने ग्रामीणों को इतना दुःखी व भयभीत कर दिया था कि अगली सुबह जब कर्फ्यू में ढील दी गयी, तो वे घरों से बाहर नहीं निकले। समीपवर्ती पंडरिया व मुंगेली में बंद का आयोजन हुआ। और कुछ हुआ हो या नहीं, मगर नेताओं की अदूरदर्शिता ने सवर्णों और हरिजनों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया। मध्यप्रदेश के प्रभारी महासचिव सांसद राम रतन राम ने भोपाल में दुःखी मन से कहा कि मंदिरों में हरिजन प्रवेश जैसे अप्रांसगिक मुद्दों को बेवजह तूल नहीं देना चाहिये। सामाजिक सद्भाव के लिहाज से प्रभारी महासचिव का कथन अपनी जगह सही है, लेकिन क्या किया जाये जबकि कुछ नेताओं में हरिजनों के बीच प्रभुत्व जमाने की इच्छा धधक रही हो। सुदूर पांडातराई में यह अवांछित घटना कतई नहीं घटती, अगर दिग्विजय सिंह बयानबाजी में संयम बरतते और सबसे बढ़कर सहयोगी सांसद जांगड़े की बात मानकर केयूर भूषण पांडातराई नहीं जाते। नेतृत्व व प्रशासन की दूरदर्शिता व समझबूझ से ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। सवर्णों को इस पर ठंडे दिमाग से विचार करना होगा कि हरिजनों को संवैधानिक और मानवीय अधिकार हासिल करने से रोकना कहां तक उचित व तर्कसंगत है।

संपूर्ण घटनाक्रम ने ग्रामीणों को इतना दुःखी व भयभीत कर दिया था कि अगली सुबह जब कर्फ्यू में ढील दी गयी, तो वे घरों से बाहर नहीं निकले। समीपवर्ती पंडरिया व मुंगेली में बंद का आयोजन हुआ। और कुछ हुआ हो या नहीं, मगर नेताओं की अदूरदर्शिता ने सवर्णों और हरिजनों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया।

० **सुधीर सक्सेना**

साक्षात्कार/दिग्विजय सिंह

'छुआछूत निवारण के लिये कटिबद्ध हूं'

पांडातराई में हुए हरिजन-सवर्ण संघर्ष के लिये सर्वाधिक दोषी दिग्विजय सिंह और केयूर भूषण को ठहराया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर वह १७ अक्टूबर को सम्मेलन में उत्तेजक बयान न देते, तो कुछ नहीं होता। भोपाल में रामरतन राम के बयान के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि श्री सिंह का कथन अनुशासनहीनता की परिधि में आता है या नहीं। प्रस्तुत हैं, २८ अक्टूबर को भोपाल में उनसे हुई बातचीत के अंश:

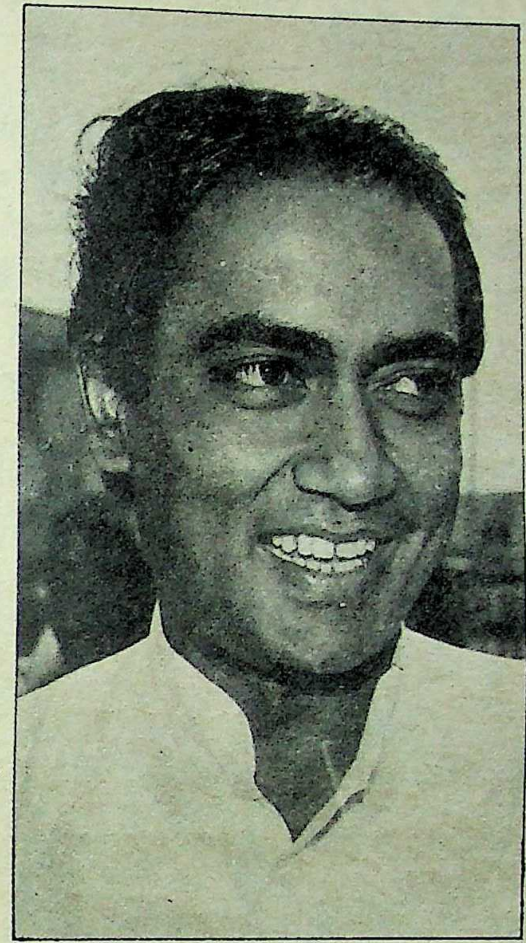

माया: १७ अक्टूबर के सम्मेलन में आपने अपने भाषण में क्या बातें कही थीं?

सिंह: मैंने कहा था कि छुआछूत मिटाने के लिये हम लोग कटिबद्ध हैं। अगर १४ नवंबर तक हल नहीं खोजा गया, तो कांग्रेस पार्टी हरिजन सेवक संघ के सहयोग से मसले को सुलझायेगी और हम मंदिर में हरिजनों के प्रवेश का आवाहन करेंगे। मूल मुद्दा यह था कि हरिजनों को खेतों में मजूरी नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही थी। इन बातों पर मैंने सांसद जांगडे और बैजनाथ चंद्राकर से चर्चा की थी और कहा था कि यह जवाबदारी सवर्णों की है कि हरिजनों पर अत्याचार न हो।

माया: सम्मेलन में और कौन-कौन उपस्थित थे?

सिंह: सम्मेलन में खेत मजदूर परिषद के अध्यक्ष झीनाभाई दरजी, निर्मला देशपांडे, केयूर भूषण, अजीत जोगी, जांगड़ जी और इंका के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

माया: क्या आपकी अधिकारियों से कोई चर्चा हुई थी?

सिंह: १७ अक्टूबर को ही बिलासपुर लौटकर (मुंगेली से) मैंने कलेक्टर उदयवर्मा से बात की थी। वह मुझसे मिलने भी आये थे। शाम को भोपाल लौटकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समस्या के शीघ्र निराकरण का निवेदन किया था।

माया: क्या सांसद केयूर भूषण ने २४ अक्टूबर को पांडातराई जाने के इरादे के बारे में आपको कोई जानकारी या सूचना दी थी?

सिंह: नहीं। उन्होंने पांडातराई जाने के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी।

माया: २४ तारीख को पांडातराई में जो कुछ हुआ, उस बारे में आप क्या कहेंगे?

सिंह: जो कुछ हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

माया: क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने सम्मेलन में जो कुछ कहा उसे कहने की कोई जरूरत नहीं थी? कई लोगों का ख्याल है कि आपने अप्रासंगिक मुद्दे उठाये।

सिंह: जरूरत इसलिये थी कि सतनामी समाज का आंदोलन चार-पांच माह से पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा था। कारण यह कि गुरु घासीदास को 'चमार' शब्द से संबोधित किया गया है और ऐसी किताबें पाठ्य-पुस्तक के रूप में चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ता से आश्वासन दिया है कि इन्हें टेक्स्ट बुक (पाठ्यक्रम) से निकाल दिया जायेगा। इस बारे में एक सरकारी समिति भी लो०नि० मंत्री दुर्गादास सूर्यवंशी की अध्यक्षता में गठित की गयी है जो ऐसे सभी उल्लेखों को देखकर निर्णय करेगी। इसके बावजूद भी सतनामी समाज में आक्रोश बना हुआ है। मेरे मत में कुछ विरोधी तत्व हरिजन समुदाय को भ्रम में डालकर कांग्रेस पार्टी से अलग करना चाहते हैं और इसीलिये वे निरंतर हरिजनों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हरिजनों को कांग्रेस से अलग करने की साजिश जोरों पर है। जब यह मसला हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा छुआछूत पखवाड़े के अंतर्गत मेरे सम्मुख लाया गया, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की नीति व सिद्धांतों के अनुरूप मत व्यक्त करूं, ताकि हरिजनों को कांग्रेस से नाराज करने के कुटिल प्रयास को दबाया जा सके।

माया: क्या राजनांदगांव के सांसद शिवेंद्र बहादुर सिंह ने आपसे बयान वापस लेने को कहा था?

सिंह: शिवेंद्र से २१ अक्टूबर की रात को दिल्ली में मेरी चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि हम टकराव की स्थिति नहीं बनाना चाहते। हम समझाबुझाकर निराकरण चाहते हैं। मैंने उनसे भी सुझाव व सहयोग मांगा था, क्योंकि उनका क्षेत्र पांडातराई से लगा हुआ है तथा यह क्षेत्र अतीत में रामराज्य परिषद का प्रभावक्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र कवर्धा से इंका विधायक श्रीमती शशिप्रभा देवी के परिवार के प्रभाव में रहा है। समस्या के निदान के लिये उनके प्रभाव के इस्तेमाल के बारे में भी मैंने शिवेंद्र से चर्चा की थी। तय हुआ था कि विस्तृत प्रोग्राम बनाया जाये। चूंकि २५, २६ व २७ अक्टूबर को सब भोपाल में रहनेवाले थे, अत: तय हुआ कि इन्हीं दिनों सब मिल बैठकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पूर्व २४ तारीख को दुर्घटना घट गयी।

माया: क्या आपने इस बारे में प्रभारी महासचिव व सांसद रामरतन राम से कोई बातचीत की या उन्हें जानकारी दी?

सिंह: रामरतन जी से दिल्ली में मिलकर चर्चा करना चाहता था। उनसे मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन फोन पर चर्चा जरूर हुई थी।

माया: उन्होंने क्या कहा था?

सिंह: मैंने उन्हें फोन पर जानकारी दी थी तो उन्होंने कहा था कि जो तुम बता रहे हो, अगर वह सही है, तो मैं 'अप्रूव' करता हूं।

माया: २४ अक्टूबर के हादसे के बाद आप अब इस मामले में क्या राय रखते हैं?

सिंह: मैं दृढ़ता से आज भी छुआछूत निवारण के लिये कटिबद्ध हूं, क्योंकि कांग्रेस की यह महात्मा गांधी के समय से नीति रही है और कांग्रेस पार्टी की क्रियाशील सदस्यता के फार्म में भी इसे मुख्य अर्हता माना गया है और इसकी प्रतिज्ञा हर क्रियाशील सदस्य को करनी पड़ती है।

माया: क्या यह सही है कि राघोगढ़ में मंदिर में हरिजनों का प्रवेश वर्जित है?

सिंह: सरासर गलत। मेरे पिताजी के समय से राघोगढ़ के मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश जारी है और हरिजनों के मंदिर-प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

० सुधीर सक्सेना

दादा का नया पैंतरा

महाराष्ट्र की राजनीति से दूर करने के उद्देश्य से राजस्थान का राज्यपाल बनाकर भेजे गये वसंत दादा पाटील महाराष्ट्र लौटने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन हाल ही उन्होंने घोषणा की है कि वह अपने ७०वें जन्मदिन अर्थात १० नवंबर को राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या दादा वास्तव में राजनीति से संन्यास ले लेंगे या वह कोई चाल खेलकर धमाके के साथ प्रदेश राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं?

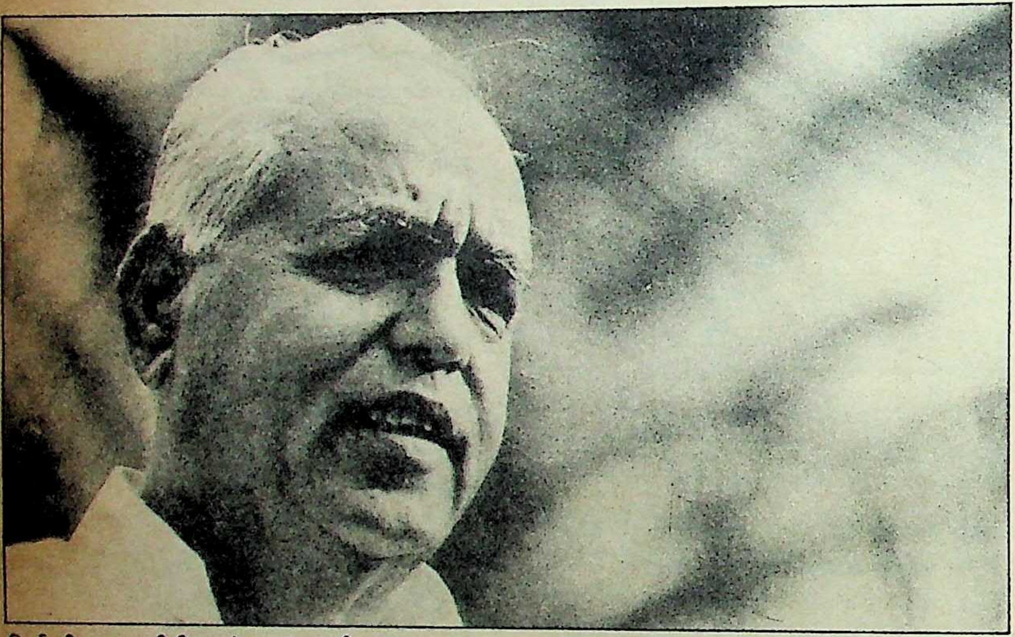

सिर्फ गीदड़ भबकी ?: वसंत दादा पाटील

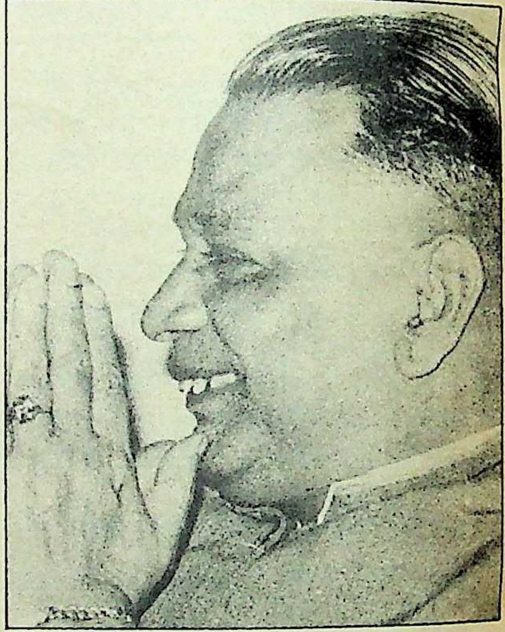

सत्ता सलामत : मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण

गीतकार शैलेंद्र की फिल्म 'तीसरी कसम' को लोग भूले न होंगे। नायक राजकपूर उर्फ हीरामन कसम खाता है कि नौटंकी की बाई को बैलगाड़ी में नहीं बिठायेगा। उसी मार्मिक दृश्य का हंसाऊ रूप राजनीति में देखना हो, तो वसंत दादा पाटील की इस घोषणा पर गौर किया जाये कि १० नवंबर तक वह राज्यपाल पद से इस्तीफा दे देंगे।

श्री पाटील का यह इस्तीफा राजनीति से संन्यास है या कांग्रेस नेतृत्व के कड़े रुख से नाराजगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यों दादा यह कहते हैं कि वह रचनात्मक कामों में पूरा समय देंगे। महाराष्ट्र के लोग यह बखूबी जानते हैं कि उनका पहला रचनात्मक उद्देश्य शंकर राव चह्वाण को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। श्री पाटील के ही शब्द हैं, "मैंने हाईकमान को जतला दिया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के बने रहने पर राज्य में कांग्रेस खतम हो जायेगी। कांग्रेस के सिपाही के नाते मैं प्रदेश में कांग्रेस को खतम होने से बचाने में जुटा रहूंगा।"

झूठी घोषणा : कसम की तर्ज पर श्री पाटील ने जुलाई में बंबई पहुंचकर पहली घोषणा कर दी कि एक अगस्त तक मुख्यमंत्री बदल दिया जायेगा। उस वक्त बोफोर्स तोपों ने राजनीतिक आसमान में बारूद की महक फैला रखी थी। राजनीति के चतुर खिलाड़ी दादा पाटील इस माहौल में पटाखा फोड़कर 'दुश्मन' को आतंकित करना चाहते थे। कुछ दिन ठंडक रही। राजस्थान के राज्यपाल श्री पाटील फिर महाराष्ट्र पहुंचे। अमरावती जाकर उन्होंने दोबारा घोषणा की कि केंद्रीय नेता फिलहाल व्यस्त हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बदलने में एक महीना और लगेगा। दादा को मनाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संगठन में महत्वपूर्ण पद देना मंजूर कर लिया, लेकिन वसंत दादा की जल्दबाजी और हठ उनके गले पड़ गये। आज हालत यह है कि कांग्रेस के नये पदाधिकारी आ गये और मुख्यमंत्री-पद पर श्री चह्वाण कायम हैं।

श्री पाटील से 'माया' ने पूछा कि प्रधानमंत्री से मिले वायदे का क्या हुआ, तो खीझकर उन्होंने कहा, "यह तो उनसे पूछिये। नये महासचिव आकर काम करने लगे और अध्यक्ष पद से राजीवजी इस्तीफा देनेवाले नहीं।" वह शायद कुछ और बोलते, परंतु उनके इर्द-गिर्द बैठे लोगों ने बात बदल दी।

इस्तीफे और संन्यास की धमकी देने का दादा पाटील का यह पहला मौका नहीं है। १९७४ में (स्व०) वसंत राव नाईक मुख्यमंत्री थे तथा वसंत दादा पाटील संगठन में सबसे बड़े नेता थे। आपातकाल लागू करने के कुछ दिन पहले श्री नाईक को हटाकर शंकर राव चह्वाण को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दादा पाटील दुखी तो थे, परंतु भयभीत भी थे। जीवन के ६० वर्ष पूरे करने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया।

दादा का उत्कर्ष : आपातकाल हटा, तो दादा के जीवन की मेनका शालिनी ताई पाटील ने दादा को राजनीति में फिर खींच लिया। बताया जाता है कि श्री पाटील की जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी थी, परंतु उन्होंने श्रीमती गांधी पर दबाव डालकर अपना वर्चस्व स्थापित करने की

योजना बनायी। उन्होंने पराजित, थकी तथा जनरोष से घबरायी श्रीमती इंदिरा गांधी पर दबाव डाला कि शंकर राव चह्वाण को मुख्यमंत्री-पद से हटाया जाये। श्री चह्वाण हटे और श्री पाटील मुख्यमंत्री बने।

इंदिरा गांधी के निधन के बाद श्री पाटील को केंद्रीय नेतृत्व ने पहला झटका तब दिया, जब श्रीमती प्रभा राव को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वह श्रीमती राव को इस पद पर देखने के इतने खिलाफ थे कि मुख्यमंत्री-पद छोड़ने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उस वक्त के वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह बंबई

निलंगेकर

मूपनार

पहुंचे। दादा की बातचीत से लगा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। शाम ५ बजे श्री सिंह दिल्ली रवाना हुए। विमान तल से लौटते हुए श्री पाटील ने राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। उन दिनों चर्चा थी कि कांग्रेस महासचिव जी०के० मूपनार से दादा की गोटी जमी है। एक महिला सांसद की शिकायत पर मूपनार से महाराष्ट्र ले लिया गया।

१३ नवंबर, १९८७ को दादा ७० साल के हो जायेंगे। इसलिए १० नवंबर को वह सांगली पहुंच जायेंगे। दादा की घोषणा के अनुसार उनका संदेशवाहक राष्ट्रपति को जाकर राजस्थान के राज्यपाल-पद से इस्तीफा सौंप देगा। यों वसंत राव राष्ट्रपति वेंकटरमन से भी कम नाराज नहीं हैं, जिन्होंने गश्ती-पत्र भेजकर बारंबार उनके गृहराज्य

ताई का दर्द

दादा की विभीषण : शालिनी ताई पाटील

शालिनी ताई पाटील जब अपने पति वसंत दादा पाटील से बहुत क्षुब्ध होती हैं, तो एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कोई एक नया शिगूफा छोड़ देती हैं। अब जब दादा एक महीने की छुट्टी लेकर बंबई और सांगली में बैठकर एक नये मुहिम की शुरुआत करने वाले थे तथा राजस्थान के राज्यपाल पद को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना चुके थे, तो शालिनी ताई ने बंबई में अचानक एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर एक छोटा-सा ढेला दादा की राजनीति के तालाब में फेंक दिया। सम्मलेन की सूचना कुछ घंटे पहले टेलीफोन पर पत्रकारों को उन्होंने खुद दी। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा यों तो उनके प्रस्तावित जवाहरलाल नेहरू सहकारी साखर कारखाना लि० के एक गुम हुए पत्र से था, लेकिन सम्मेलन के जरिये ताई दादा को अपने होने का अहसास कराना चाहती थीं, क्योंकि दादा का 'घर' सांगली ताई के जन्म स्थान सतारा से थोड़ी ही दूरी पर है और बकौल ताई, "कुछ लोगों ने जानबूझ कर उनके क्षेत्र (कोरगांव) का विकास नहीं होने दिया।"

सतारा में कोरेगांव तथा खटाऊ तहसील हमेशा से पिछड़े रहे हैं। ताई ने 'माया' को बतलाया, "धोम तथा कान्हेर सिंचाई परियोजनाओं के कारण यहां की उपजाऊ जमीन पर गन्ने की फसल तो ज्यादा होती है, लेकिन इन तहसीलों में गन्ना कारखाना न होने के कारण किसान काफी दिक्कत महसूस करते रहे। मैंने यहां के किसानों के बीच काफी काम किया और उन्हें एकजुट कर कोरेगांव में जवाहरलाल नेहरू सहकारी साखर कारखाना खोलने के लिए तैयार किया। १९८१ में सारी औपचारिकताएं पूरी कर महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी गयीं, ताकि मंजूरी के लिए वह उसे केंद्र के पास भेज सके। कुछ कारणोंवश इसमें विलंब हुआ और केंद्र के पास उसे १९८३ में भेजा जा सका। लेकिन तब तक केंद्र की नीति में परिवर्तन हो चुका था। नयी नीति में यह तय किया गया था कि जिस जिले में तीन या अधिक कारखाने हों, वहां पर कोई नया कारखाना न खोला जाये। १९८४ में मैं प० महाराष्ट्र के १२ सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें स्व० यशवंत राव चह्वाण भी शामिल थे; लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिली। अंततः दिसंबर १९८६ में नीति में परिवर्तन कर नये निर्देश जारी किये गये। हमने ९ फरवरी, १९८७ को निदेशक, साखर निदेशालय के पास प्रारंभिक आवेदन पत्र दिया; फिर आवश्यक दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों के साथ पूर्ण आवेदन पत्र २० मार्च, १९८७ को दाखिल किया।"

श्रीमती शालिनी ताई के अनुसार, "नये निर्देश जारी किये जाने के बाद सबसे पहला प्रस्ताव उन लोगों ने साखर निदेशालय के पास भेजा था। महाराष्ट्र सरकार ने ३० जुलाई, ८७ को उनके प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजे जाने की सूचना दी। लेकिन हमें उस समय बेहद आश्चर्य हुआ, जब स्क्रीनिंग कमेटी की २८ अगस्त, १९८७ को दिल्ली में हुई बैठक में हमारे प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हुआ। बाद में पता चला कि हमारा प्रस्ताव उनके पास पहुंचा ही नहीं, जबकि नये निर्देश के अनुसार सर्वप्रथम प्रस्ताव भेजने वाले हम लोग थे। हमारे बाद किसी और के द्वारा प्रस्तुत कमला नेहरू साखर कारखाना के प्रस्ताव को कमेटी के पास विचारार्थ भेज दिया गया था। हमने तुरंत महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों आदि से संपर्क किया, लेकिन हमें वही जवाब मिला कि हमारा प्रस्ताव ३० जुलाई, १९८७ को दिल्ली भेज दिया गया था। २ सितंबर, १९८७ को केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव न पाने की पुनः सूचना दी और १५ सितंबर, १९८७ को मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को हमारे प्रस्ताव को विचारार्थ भेजने के लिए पत्र लिखा, फिर टेलेक्स से रिमाइंड भी किया। हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे हमारे प्रस्ताव को सील बंद कर हमें दे दें, ताकि हम उसे कूरियर सर्विस से तुरंत उद्योग मंत्रालय को भेज दें। लेकिन हमारी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित हुई। अंततः हमें अदालत का सहारा लेना पड़ा।"

बंबई उच्च न्यायालय में २९ सितंबर, १९८७ को दाखिल याचिका (याचिका नं० ४८८०/१९८७) पर न्यायमूर्ति शाह एवं सुरेश ने विचार किया और उनके प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजने का निर्देश दिया।

शालिनी ताई मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण की आलोचना जरूर करती हैं, लेकिन उनके प्रस्ताव को जानबूझ कर दबा या गायब कर देने आदि घपलेबाजी में उनका हाथ कतई नहीं मानतीं। वह दादा का बिना नाम लिये उन्हें यह कहकर आरोपों के घेरे में जरूर घसीट लेती हैं कि उनकी महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली में अच्छी पहुंच है। सतारा में जवाहरलाल नेहरू सहकारी साखर कारखाना स्थापित हो जाने पर दादा के सरकार साम्राज्य को भारी धक्का पहुंचेगा।

२६ अक्तूबर, १९८७ को जयपुर छोड़ कर बंबई आ पहुंचे दादा १३ नवंबर को सांगली में, अपने जन्म दिन पर आयोजिन रैली को और भी प्रभावशाली बनाने की तैयारियों में जुट गये हैं, लेकिन उन्हें भी डर है कि कहीं ताई ऐन मौके पर कोई गहरा दांव न मार जायें। इसलिए इस रैली में विश्वनाथ प्रताप सिंह के शामिल होने की खबर को वह 'दुश्मनों द्वारा उड़ायी गयी अफवाह' कह कर कांग्रेस उच्च कमान को भरमाना भी चाहते हैं और धमकाना भी। सभी जानते हैं कि दुश्मन नंबर-एक कौन है उनका— निश्चय ही मुख्यमंत्री चह्वाण नहीं।

—बंबई ब्यूरो

जाने पर रोक लगा दी। हालांकि, पत्र सभी राज्यपालों को भेजे गये थे, परंतु सब जानते हैं कि श्री पाटील ही उनका असली निशाना थे।

वसंत राव का दिल्ली के नेताओं से मोह भंग हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने इंटेलिजेंस (खुफिया) रपट मंगाकर पता लगा लिया है कि उनके इस्तीफे या पार्टी छोड़ने से महाराष्ट्र में कांग्रेस को खतरा नहीं है। अनेक केंद्रीय तथा महाराष्ट्र के नेताओं ने उन्हें राज्यपाल-पद से निकालने की मांग भी कर दी है। सबसे बड़ी 'विभीषण' तो उनकी पत्नी शालिनी ताई साबित हो रही हैं, जिन्होंने एक तो परोक्षत: उन पर या उनके समर्थकों पर चीनी कारखाने संबंधी कागजात गुम करा देने का आरोप लगाया और दूसरी तरफ दादा पाटील को सलाह दी, "शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए वह घर बैठकर आराम करें, केंद्रीय नेतृत्व को इस्तीफे की धमकी देना ठीक नहीं है।" इसके पहले १९८३ में भी उन्होंने दादा को संन्यास लेकर आराम करने की सलाह दी थी, क्योंकि वह खुद मुख्यमंत्री-पद की दावेदार थीं।

श्री पाटील भी समझ गये हैं कि इस धर्मपत्नी से उलझना मुश्किल है, इसलिए खिल्ली उड़ाये जाने के भय से वह यह कह देते हैं कि मेरे लिए शालिनी ताई मर चुकी हैं। राज्यपाल-पद छोड़ने की धमकी से उनके समर्थक भले घबराये हों और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मिन्नतें कर रहे हों, परंतु कांग्रेस या विपक्ष इससे अप्रभावित ही लगता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण ने तो कहा है, "१३ नवंबर के बाद अपनी राय दूंगा।" उनके चेहरे पर फैली मुस्कान से पता चलता है कि वह इस धमकी से कितने निश्चिंत हैं।

रा०सु० गवई

नासिक राव तिरपुड़े

कांग्रेस के नये महासचिवों में केदार नाथ सिंह श्री पाटील के प्रशंसकों में से एक हैं। उन्हें लगता है कि 'देशभक्त दादा' पार्टी को परेशानी में डालने वाला कोई काम नहीं करेंगे। और-तो-और शिवसेना के नेताओं को भी लगता है कि दादा को जरूरत से ज्यादा महत्व देना ठीक नहीं होगा। दादा-पवार गुट के उम्मीदवार प्रभाकर धारकर को रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से हराने में शिवसेना की प्रमुख भूमिका रही। दादा के इस्तीफे पर बोलते हुए शिवसेना के एकछत्र नेता बाल ठाकरे ने कहा, "यह उनका आपसी मामला है। वे (कांग्रेसी) आपस में निबट लें। मुझसे न तो दादा की बातचीत हुई और न कोई संदेश आया। हम शेकाप-शेतकरी संघटना-शिवसेना की नयी धुरी बनाना चाहते हैं।"

विश्वनीयता खतरे में: हालांकि, मराठा विरोधी लाबी के एक प्रमुख नेता भूतपूर्व उपमुख्यमंत्री नासिक राव तिरपुड़े ने दादा पाटील से अक्तूबर के पहले सप्ताह में मिलकर यही कहा था कि उन्हें कांग्रेस से इतना मिल चुका है, जिसके कि वह पात्र नहीं थे। बताया जाता है कि तिरपुड़े ने, जो दादा के मुख्यमंत्रित्व के जमाने में उपमुख्यमंत्री थे, याद दिलाया कि उन्होंने कांग्रेस-इ नेता के रूप में उनका (दादा का) मुख्यमंत्री-पद के लिए विरोध किया था, परंतु हाईकमान के कहने पर मंजूर किया। दादा के कहने पर शिवाजीराव निलंगेकर पाटील को उनका वारिस (मुख्यमंत्री) बनाया गया, जो उस वक्त विधानसभा के सदस्य तक नहीं थे।

आज श्री पाटील के सामने राज्यपाल-पद छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति रह चुके रा०सु० गवई ने कहा, "वह मजाक के पात्र बन चुके हैं। बारंबार मुख्यमंत्री बदलने की भविष्यवाणी करने तथा राज्यपाल-पद से इस्तीफे की धमकी देकर उन्होंने खुद की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया।"

—बंबई ब्यूरो

पुरुषों के लिये अनुपम शक्ति वर्द्धक
रसायनवटी

बढ़ती हुई आयु, रोज़मर्रा के कामों से उत्पन्न थकान अथवा अप्राकृतिक आचरणों से क्षीण हुई शक्ति को **रसायन वटी** जल्द पूरा करती है। धातु परिपोषण प्रक्रिया (Metabolism) को सुधार कर पूरे शरीर का पोषण कर पूर्ण सशक्त बनाती है। **रसायन वटी** प्रसिद्ध एवं प्राचीन राजवैद्य रसायनशाला द्वारा निर्मित पुरुषों की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ, विश्वसनीय, असरदार एवं बेजोड़ आयुर्वेदिक टानिक है जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी नवयौवन, शक्ति व स्फूर्ति के लिए **रसायन वटी** का सेवन करें। **रसायन वटी** एक हानि रहित व स्थायी लाभप्रद औषधि है, जो आयु के हर आयाम पर सतत निरोग व सक्रिय बनाये रखती है।

रसायन वटी
अनुपम शक्तिवर्धक
राजवैद्य
शीतल प्रसाद एण्ड संस
23, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

200 गोली पैकिंग रु. 70/-, 60 गोली पैकिंग रु. 27/50 स्थानीय कर अलग। स्थानीय विक्रेता से लें या वी.पी. द्वारा मंगवायें। वी.पी. खर्च रु. 10/- अलग।

निर्माता :
राजवैद्य शीतल प्रसाद एण्ड संस
4771/23 दरियागंज, नई दिल्ली– 110002
शाखाएं : दिल्ली, नागपुर, इन्दौर, गाजियाबाद

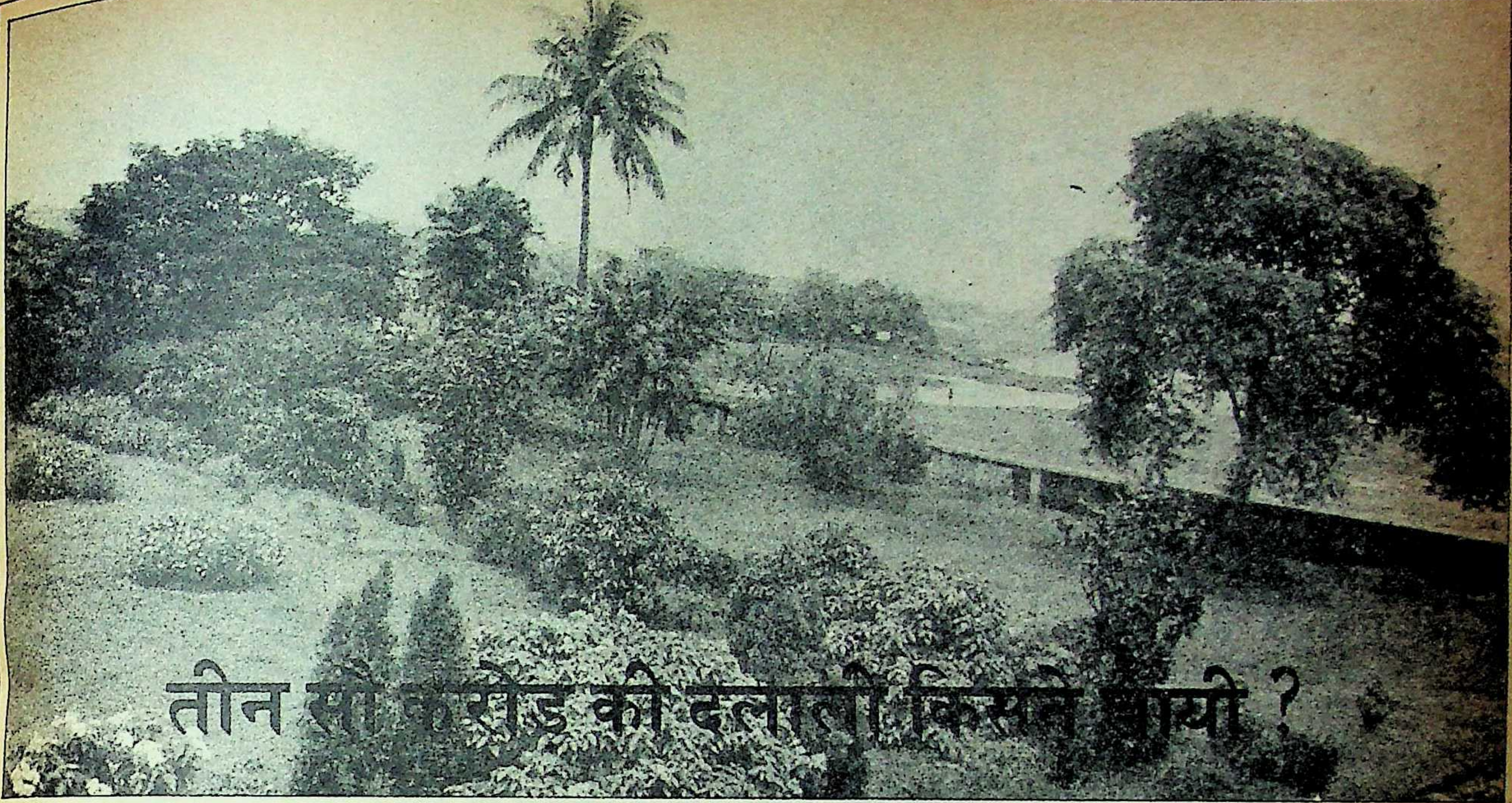

तीन सौ करोड़ की दलाली किसने खायी ?

कितनी दलाली खायी ? : व्यवसायियों को लीज पर दिया गया बेलीलियस पार्क

रडन स्क्वैयर के मामले में आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर लग रहा था कि उसने पार्टी फंड के लिए करोड़ों रुपए घूस लेकर रडन स्क्वैयर के विकास का कार्य कालेधन के लिए कुख्यात एक व्यवसायी को सौंप दिया है, लेकिन अब कलकत्ता ही नहीं हावड़ा, हुगली और चौबीस परगना जिलों के अनेक पार्कों और सरकारी जमीनों को लीज पर देने व बेचने के प्रकरण भी सामने आने लगे हैं। ऐसे १४ सौदों में तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक की घूस लेने के आरोप हैं। प्रदेश कांग्रेस-इ ने इन मुद्दों को लेकर आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। क्या ज्योति बाबू अपने दामन पर लग रहे धब्बों को मिटाने के लिए उक्त आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

वह तारीख थी, १३ सितंबर, १९८७। केंद्र सरकार के वी०आई०पी० हास्टल के निजाम पैलेस में केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी के नेतृत्व में बंद कमरे में जरूरी बैठक हो रही थी। उस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी शीर्षस्थ नेता, महामंत्री तथा कलकत्ता, हावड़ा, हुगली और चौबीस परगना के अधिसंख्य कांग्रेसी विधायक और सांसद उपस्थित थे। उस गुप्त बैठक में उन चार जिलों के विधायकों, सांसदों और कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों ने जो जानकारी दी और शिकायत की, उससे यही आरोप उभरकर सामने आया कि कलकत्ता, हावड़ा, हुगली और चौबीस परगना में पार्कों और प्लाटों के आवंटन और लीज संबंधी १४ सौदों में ३०० करोड़ रुपए की घूसखोरी हुई है। जिन इलाकों के भूमि-आवंटन को लेकर रिश्वतखोरी का आरोप है, वे हैं—चायना टाउन, रडन स्क्वैयर, बेलीलियस पार्क, साल्ट लेक सिटी, चूंचुड़ा नगरपालिका का करघाटा मौजा, अलीपुर जेल परिसर, ईस्टर्न बाईपास के पास धापा आदि। कलकत्ता कार्पोरेशन में विपक्षी दल के नेता शिव कुमार खन्ना ने बताया, "कलकत्ता महानगर के रडन स्क्वैयर, न्यू मार्केट, लैंसडाउन मार्केट, लेक मार्केट, न्यू अलीपुर मार्केट और कुछ पार्कों के लीज संबंधी सौदों में कलकत्ता के मेयर और सी०पी०एम० के एक गुट के नेताओं ने लगभग २०० करोड़ रुपए का गुप्त लेन-देन किया है।" इसके पहले शिव कुमार खन्ना ने एक अलग बयान में बताया था कि कलकत्ता के चायना टाउन में सी०पी०एम० समर्थकों और 'सीटू' के एक वर्ग ने गैरकानूनी प्लाट सौदे में १०० करोड़ रुपए 'कटमनी' (पगड़ी) के रूप में लिये हैं। इसी के साथ प्रियरंजन दासमुंशी ने साफ-साफ आरोप लगाया कि सी०पी०एम० के कुछ मंत्रियों की साठगांठ से मुख्यमंत्री ज्योति बसु और मेयर कमल बसु ने पार्क, प्लाट और जमीन के लीज के मामले में करोड़ों रुपए की घूस ली है। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने जो ब्योरा दिया, उसके अनुसार शहरी क्षेत्र में जमीन के गैरकानूनी लेन-देन में लगभग ३०० करोड़ रुपए की 'कटमनी' ली गयी है। इस ३०० करोड़ रुपए की घूस लिये जाने के आरोप के संबंध में सारे तथ्य और प्रमाण इकट्ठा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विशिष्ट अधिवक्ता और सांसद भोलानाथ सेन के नेतृत्व में ११ सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। इस समिति के सदस्यों में अधिसंख्य विधायक, सांसद, स्थानीय निकायों के सदस्य और विधि-विशेषज्ञ हैं। इसे तथ्य और प्रमाण इकट्ठा करने व उन्हें प्रकाश में लाने और उन्हें विपक्षी नेताओं को देने का अधिकार दिया गया है। इस प्रसंग में प्रियरंजन दासमुंशी ने घोषणा की, "३१ दिसंबर तक हम मुख्यमंत्री ज्योति बसु को बेनकाब कर देंगे। सारे भारत में ज्योति बाबू ने एक स्वामीजी जैसी छवि बना रखी है, लेकिन वाममोर्चा सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार समाया हुआ है। भ्रष्टाचार संबंधी कागजात अब मेरे पास आने लगे

हैं। उनके मिल जाते ही हम ज्योति बसु को बेनकाब कर देंगे।''

पार्क-प्लाट लीज में काले धन के लेन-देन और रिश्वत लिये जाने के मामले को लेकर सिर्फ कांग्रेस और दो केंद्रीय मंत्रियों ने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, कलकत्ता कार्पोरेशन में उसके दो कौंसिलरों, नक्सलियों के एक वर्ग, झारखंड पार्टी और पश्चिम बंगाल के विशिष्ट पत्रकार वरुण तक ने आवाज उठायी है।

कलकत्ता कार्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के कौंसिलर शांति लाल जैन और श्यामसुंदर गोयनका ने प्रियरंजन दासमुंशी का समर्थन किया है। रडन स्क्वैयर सौदे का विरोध करते हुए इन लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार की दृष्टि से रडन स्क्वैयर कांड बोफोर्स कांड का बाप है। इस भ्रष्टाचार में राज्य में सत्तारूढ़ कुछ शीर्षस्थ लोग, उनके आत्मीयजन और इष्टमित्र लिप्त हैं। इसलिए इस संबंध में भाजपा का नारा है— 'पार्क बेचना पाप है, बोफोर्स का बाप है।'

पूर्व विदेशमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी अभी कलकत्ता आये थे। उस समय उन्होंने भाजपा नेताओं को इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने का निर्देश दिया।

रडन स्क्वैयर के प्रसंग में वरुण बाबू का कहना है, ''बताया जाता है कि कलकत्ता में सबसे अधिक काला धन अरुण बाजोरिया के पास है। वह जब स्विट्जरलैण्ड जाते हैं, तब उनको छोड़ने बैंक के चेयरमैन स्तर के लोग हवाई अड्डे पर आते हैं। ऐसे अरुण बाजोरिया ने रडन स्क्वैयर का काम पाने के लिए जरूर पहले से मोटी रकम दी है। (देखिए 'माया' १५ सितंबर, १९८७)।

सी०पी०एम० के भ्रष्टाचार संबंधी इस मामले को प्रकाश में लाने के कारण सी०पी०एम० की तरफ से 'गणशक्ति' के संपादक अनिल विश्वास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रियरंजन दासमुंशी तथा 'टेलीग्राफ' के प्रकाशक और संपादक के विरुद्ध एक करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से साफ-साफ बयान देने पर भी केंद्रीय सूचना मंत्री अजित पांजा, भाजपा कौंसिलर शांति लाल जैन और श्यामसुंदर गोयनका, पूर्व मुख्यमंत्री पी०सी० सेन, विधानसभा में विपक्षी दल के नेता अब्दुल सत्तार, विधायक सुलतान अहमद, पत्रकार वरुण सेन गुप्त या कलकत्ता कार्पोरेशन में कांग्रेस दल के नेता शिवकुमार खन्ना के विरुद्ध सी०पी०एम० ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया।

COMMERC
INI NAIDU S

कुख्यात उद्योगपति का साथ: मुख्यमंत्री ज्योति बसु उद्योगपति अरुण बाजोरिया (बीच में) के साथ

कलकत्ता के प्रकरण: रडन स्क्वैयर के अलावा सत्यनारायण पार्क, न्यू मार्केट, लेक मार्केट, लैंसडाउन मार्केट, न्यू अलीपुर मार्केट और चायना टाउन में लीज पर प्लाट दिये जाने और व्यवसायियों को गैरकानूनी सुविधा मिलने को लेकर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिलने लगी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने आंकड़े देते हुए ३१ अगस्त को कहा था, ''न्यू मार्केट में जहां जमीन का दाम २५ हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर है, वहीं वह सिर्फ १०८० रुपए में लीज पर दी गयी है। इसी तरह न्यू अलीपुर मार्केट में जमीन ८७ रुपए तथा लेक मार्केट और लैंसडाउन मार्केट में ४६५ रुपए प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से लीज पर दी गयी है। प्रियरंजन बाबू का आरोप है कि इन चार मार्केटों से डेवलपरों को बाजार दर के मुकाबले में लगभग १५० करोड़ रुपए का फायदा मिला। इसका एक बड़ा हिस्सा सी०पी०एम० के कोष में जा रहा है।''

दासमुंशी के कथन में दम नजर आता है, क्योंकि प्राइवेट डेवलपरों से लीज के ये सब करार विधानसभा के पिछले चुनाव के समय हुए। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति बसु इनकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसके अलावा स्वयं सी०पी०एम० मेयर ने कहा है कि लीज के मामले में मैंने जो कुछ किया है, वह मुख्यमंत्री के निर्देश से किया है।

दूसरी तरफ चायना टाउन में खास सरकारी जमीन का आवंटन विचित्र ढंग से हुआ है। इसके लिए कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी। जमीन भी धनाढ्य लोगों को मिली है। कलकत्ता के उपनगर चायना टाउन में नये व्यवसायियों की भीड़ है। कलकत्ता कार्पोरेशन में विपक्षी दल के नेता शिवकुमार खन्ना ने चायना टाउन में भूमि आवंटन को लेकर १०० करोड़ रुपए के लेन-देन की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे सी०पी०एम० के श्रमिक संगठन सीटू के स्थानीय नेताओं का हाथ है।

साल्ट लेक में अनियमितताएं: इसी के बाद कलकत्ता के बाहरी हिस्से साल्ट लेक में भूमि हस्तांतरण का प्रसंग आया। इस प्रसंग में प्रियरंजन दासमुंशी और विधायक साधन पांडे आदि कांग्रेसी नेताओं ने यहां १९७८ से १९८७ तक जो भूमि-आवंटित हुई है, उसकी कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में प्रियरंजन दासमुंशी का कहना है कि हमारे पास ऐसी खबर है कि भूमि के लिए जो प्रार्थना पत्र दिये गये थे, उनसे संबंधित बहुत-सी फाइलें खो गयी हैं। न्यायाधीश से जांच कराने पर सनसनीखेज तथ्य प्रकाश में आयेंगे।

इसके बाद साल्ट लेक की जमीन के बारे में राज्य सरकार द्वारा मौन तोड़े जाने की खबर १४ सितंबर को मिली। १३ सितंबर को राज्य के स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया, ''साल्ट लेक के भूमि-आवंटन में कही किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। ७० प्रतिशत भूमि का आवंटन लाटरी के माध्यम से हुआ है तथा शेष ३० प्रतिशत भूमि के आवंटन का जिम्मा सरकार का है।''

फिर साल्ट लेक में व्यवसायियों को प्लाट कैसे मिले ? यह सवाल करने पर उस प्रवक्ता ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राज्य के स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार चोरी-छिपे भूमि का जो हस्तांतरण होता है, उसे रोकना प्रायः असंभव है, फिर भी साल्ट लेक अथारिटी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उधर साल्ट लेक में भूमि का जो हस्तांतरण हो रहा है, वह मुख्य रूप से 'पावर आफ एटार्नी' के माध्यम से हो रहा है। उसे रोकने के लिए अब भी सरकार के पास कोई कानून नहीं है। व्यवसायी लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं।

भ्रष्टाचार का विरोध: केंद्रीय मंत्री अजीत पांजा और केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी

ग्रीनवुड का मामला: साल भर से एक मामला और अखबारों में छाया हुआ है और वह है 'ग्रीनवुड' द्वारा मकान बनाने का मामला। 'वर्तमान' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार कार्पोरेशन ने बेहाला पर्णश्री में गैरकानूनी ढंग से ग्रीनवुड को मकान बनाने की स्वीकृति दी है। कलकत्ता कार्पोरेशन के १३२ नंबर वार्ड में बहुत बड़े भूखंड पर ग्रीनवुड हाउसिग कार्पोरेशन मकान बना रहा है। यहां के निवासियों का कहना है कि जहां मकान बन रहा है वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। तीन तरफ दीवार है तो एक तरफ पक्की सड़क और ताल है। ग्रीनवुड ने वह दीवार तोड़कर कालोनी के बीच से रास्ता बना लिया है। कार्पोरेशन ने स्थगनादेश से १९८६ में इस मकान का बनना रोक दिया था, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से उस स्थगनादेश को निरस्त कर दिया गया और इस समय ग्रीनवुड हाउसिग कोआपरेटिव द्वारा मकान बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल, विवाद की जड़ यही है कि स्थगनादेश के बाद 'ग्रीनवुड' को दोबारा मंजूरी मिल गयी।

स्थानीय कौंसिलर शोभन चटर्जी के अनुसार यह सरकारी जमीन है। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर भारत आये, उन्हीं को बेहाला पर्णश्री में बसाने की व्यवस्था की गयी।

१९८६ में स्थगनादेश जारी होने पर 'ग्रीनवुड' ने काम बंद कर दिया, लेकिन २३ मार्च को विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही ग्रीनवुड ने फिर अपना काम शुरू कर दिया। शोभन बाबू ने बताया कि १४ नवंबर को कमेटी के चेयरमैन निर्मल मुखर्जी के कहने पर इंजीनियर कमलेश मुखर्जी ने स्थगनादेश निरस्त करने का निर्देश दिया। कार्पोरेशन के मेयर-इन-कौंसिल के सदस्य रथीन दास शर्मा से पूछने पर उन्होंने ये सारी बातें स्वीकार कीं, लेकिन उन्होंने यह बताया कि ग्रीनवुड को काम शुरू करने का नहीं, कारण बताने का आदेश दिया गया था। रथीन बाबू का कहना है, हमने जब ग्रीनवुड वालों को कारण बताओ नोटिस दी तब उन लोगों ने राज्य सरकार के शरणार्थी पुनर्वास विभाग में जाकर आवश्यक अनुमति ले ली।

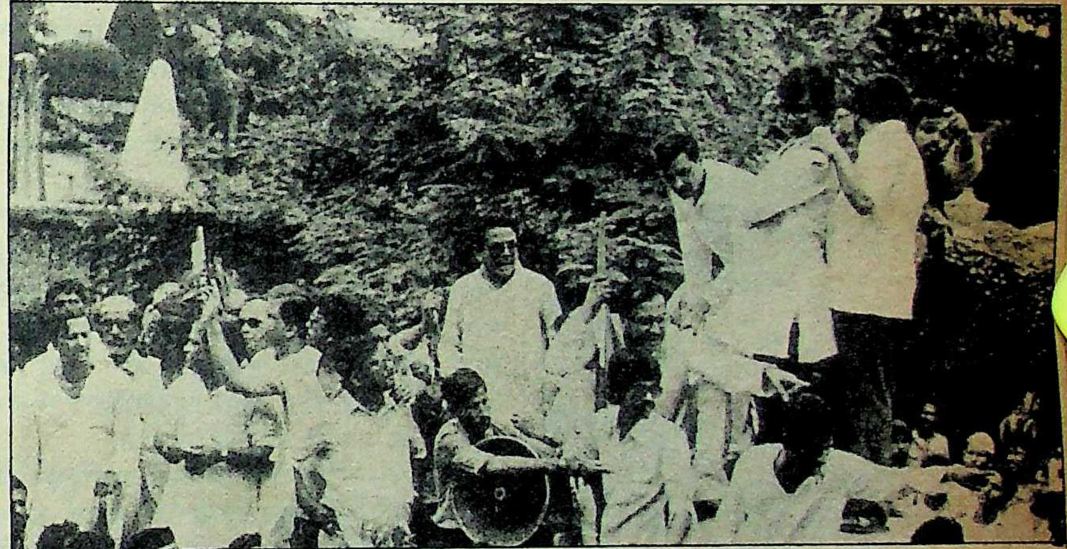

कांग्रेस-इ का विरोध प्रदर्शन: केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए

कौंसिलर शोभन चटर्जी का सवाल है कि क्या इस मामले में आवश्यक अनुमति देने का अधिकार शरणार्थी पुनर्वास विभाग को है ? राज्य के शरणार्थी पुनर्वास विभाग के उपसचिव डी०के० दास गुप्त से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि अनुमति देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कालोनी की सहकारी समिति की तरफ से गायत्री चक्रवर्ती ने बताया, "ग्रीनवुड के पीछे सी०पी०एम० की ताकत काम कर रही है। हमारी तरफ से विरोध किया गया, तो राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री रबीन मुखर्जी स्वयं इस इलाके में आये। उन्होंने कई दिनों तक ग्रीनवुड को आश्वासन दिया और हमें समझाया। उन दिनों रबीन बाबू मंत्री थे। सी०पी०एम० के एक वरिष्ठ नेता का वरदहस्त पाकर स्वाभाविक रूप से ग्रीनवुड की हिम्मत बढ़ गयी।

१०० बीघा जमीन का मामला: कलकत्ता में सरकारी जमीन घोटाले का यही अंत नहीं है। 'ईस्टर्न मेट्रोपालिटन बाइपास' के बगल में अम्बेडकर ब्रिज के पास कलकत्ता कार्पोरेशन और राज्य के सिंचाई विभाग की लगभग १०० बीघा जमीन पर ऐसे व्यवसायियों ने कब्जा कर रखा है, जिन पर एक विशेष राजनीतिक दल का वरदहस्त है। इन व्यवसायियों में से कुछ ने कार्पोरेशन से ट्रेड लाइसेंस भी ले लिया है। जमीन पर इस अवैध कब्जे और कार्पोरेशन की निष्क्रियता के पीछे जानकार लोग कुछ और ही देख रहे हैं।

इस संबंध में जो विवरण मिला उसके अनुसार करीम खां और जावेद मियां के नेतृत्व में इस जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। लेटर पैड छपवाकर ये लोग अपने को इस जमीन का मालिक कहने लगे हैं। इन लोगों ने बहुतों को कारखाना खोलने के लिए 'रेंटल लीज' पर जमीन दी है। सरकारी जमीन के इन फर्जी मालिकों ने अब तक इस तरह काफी पैसा कमा लिया है। जमीन के इस धंधे में अनेक लोग जुड़े हुए हैं।

पता चला कि कई माह पहले चौभागा पंपिग स्टेशन क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में कार्पोरेशन के कई कौंसिलर, पुलिस कर्मचारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी उस स्थल का निरीक्षण करने गये। उस समय कई कारखानों के निर्माण का काम देखकर उन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। खोजखबर लेने पर पता चला कि वह जमीन कार्पोरेशन की है। उसके बाद और जानकारी करने पर पता चला कि आसपास की जमीन भी करीम खां और जावेद मियां ने विभिन्न नामों से एलाट कर रखी है। निर्माण कार्य को लेकर अवैध कब्जा करनेवालों और निरीक्षण पर गये लोगों के बीच कहासुनी हो गयी।

जनप्रतिनिधियों को धमकी देते हुए उनमें से एक ने एंटाली के पूर्व विधायक और सी०पी०एम० नेता मुहम्मद निजामुद्दीन का नाम लिया और अपने

को उनका दामाद बताया। पता चला है कि उस घटना के बाद कई क्षुब्ध कौंसिलरों ने निजामुद्दीन से संपर्क किया, तो निजामुद्दीन ने कहा कि मेरा वैसा कोई दामाद नहीं है।

चूंचुड़ा काण्ड: इसके बाद हावड़ा के बेलीलियस पार्क लीज और सी०पी०एम० द्वारा संचालित चूंचुड़ा नगरपालिका के अधीन करघाटा मौजा में भूमि आवंटन की घटनाएं भी हुईं। हावड़ा जिला और हुगली जिला की इन घटनाओं ने जनमानस को झकझोर दिया है।

२० जुलाई सोमवार को चूंचुड़ा नगरपालिका के वर्तमान बोर्ड की पहली वर्षगांठ के दिन ही उसके चेयरमैन अमिय नंदी ने विदा ले ली। सी०पी०एम० के एक गुट का विरोध ही समय से पहले अमिय बाबू के विदा होने का कारण बताया जाता है। शिकायत मिली है कि जाली कागजात के जरिये लगभग २० बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त हुई है। इस जमीन का दाम लगभग ५० लाख रुपए है। चेयरमैन अमिय बाबू ने इस अवैध लेन-देन का डटकर विरोध किया था। उसी के लिए उनको चेयरमैन के पद से हटना पड़ा।

सी०पी०एम० के साथ: 'गणशक्ति' के संपादक अनिल विश्वास

यह जमीन चूंचुड़ा के करघाटा मांजा में है। बिक्री के बाद नगरपालिका के एक प्रभावशाली गुट के पक्ष में जमीन का स्वामित्व दर्ज करने के लिए अध्यक्ष पर दबाव डाला। अध्यक्ष अमिय बाबू ने उसमें अड़ंगा लगाया। दो सी०पी०एम० कमिश्नर नंद बख्शी और वरुण गांगुली ने झटपट इस केस को फिनांस कमेटी (वित्त समिति) के पास भेज दिया। इस कमेटी के चेयरमैन हैं, सुशांत घोष। सुशांत बाबू वहां सी०पी०एम० की तीन लोकल कमेटियों में से एक के सचिव भी हैं।

फिनांस कमेटी ने कितनी जल्दीबाजी में उस जमीन के स्वामित्व के संबंध में राय दी, उसका भंडाफोड़ ज्ञानतोष दास ने किया है। ज्ञानतोष बाबू आर०एस०पी० के सदस्य म्युनिसिपल कमिश्नर और फिनांस कमेटी के सदस्य हैं। गत १८ जुलाई को चूंचुड़ा म्युनिसिपल बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें उस विवादित जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण के बारे में विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ। उसी बैठक में प्रस्ताव रखकर स्वामित्व हस्तांतरण का विरोध आर०एस०पी० के ज्ञानतोष बाबू के साथ सी०पी०एम० के शैलेन मजूमदार ने भी किया।

उस दिन म्युनिसिपल बोर्ड की बैठक में कांग्रेसी कमिश्नर प्रसून मजूमदार और स्वपन दास के आग्रह पर ज्ञानतोष बाबू ने यह भी कहा कि उस जमीन के साथ खास सरकारी जमीन भी बेची गयी है।

बेलीलियस पार्क का मामला: हावड़ा के बेलीलियस पार्क का मामला भी रडन स्क्वैयर जैसा ही है। यहां भी विकास कार्य के नाम पर प्राइवेट डेवलपरों को पार्क लीज पर देने का मामला है। बेलीलियस पार्क व्यवसायियों को दिये जाने के विरोध में यहां कांग्रेस ने तीव्र आंदोलन छेड़ा। इसी आंदोलन के क्रम में एक दिन 'हावड़ा बंद' रखा गया। यहां भी म्युनिसिपलिटी के कांग्रेसी कौंसिलरों का आरोप है कि पार्क के हस्तांतरण में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि हावड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष आलोकदूत दास ने कहा है कि ये सब आरोप राजनीतिक स्वार्थ के कारण हैं। लेकिन पार्कों में, बिजनेस कांप्लेक्स बनाने के वामपंथी निर्णय का विशिष्ट बुद्धिजीवियों ने भी विरोध किया है। साहित्यकार समरेश बसु, अर्थशास्त्री डा० भवतोष दत्त और कवि अन्नदाशंकर राय ऐसी परियोजनाओं के विरोधी हैं।

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया: रडन स्क्वैयर के मामले में मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पहली बार ११ सितम्बर के 'बंद' के दिन जबान खोली। उस दिन शाम को सचिवालय में उन्होंने पत्रकारों से कहा, अरुण बाजोरिया यदि कांग्रेसियों और दिल्ली के दबाव में आकर रडन स्क्वैयर परियोजना से हट जाते हैं, तो हम ही उसे मूर्त रूप देंगे।

यहां उल्लेखनीय है कि कांग्रेसियों के आंदोलन और प्रतिकूल जनमत के कारण अरुण बाजोरिया ने समाचार पत्र के माध्यम से घोषणा की है कि मैं रडन स्क्वैयर परियोजना में रुपए नहीं लगाऊंगा।

मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया के साथ-ही-साथ एक और प्रतिक्रिया हुई, जिसकी खबर सुधी पाठकों को जरूर होगी। बंद के दिन ११ सितम्बर को सबेरे मुख्यमंत्री ने मेयर कमल बसु से टेलीफोन पर कहा, रडन स्क्वैयर के बारे में समाचार पत्रों को उलटा-सीधा बयान न दें। उससे परेशानी होगी। रिपोर्टरों से ज्यादा बात न करें।

यहां उल्लेखनीय है कि मेयर कमल बसु ने इसके पहले रडन स्क्वैयर संबंधी करार के बारे में एक बार कहा था कि मैंने ज्योति बाबू के भानजे अमल दत्त के निर्देश से तो दूसरी बार कहा था कि स्वयं ज्योति बसु के निर्देश से यह काम किया है।

सी०पी०एम० की प्रतिक्रिया: पार्क लीज घोटाले को लेकर सी०पी० एम० के अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, वह ध्यान देने योग्य है। रडन स्क्वैयर को लेकर कांग्रेस के आंदोलन और अन्य पार्कों के लीज संबंधी भ्रष्टाचार की लगातार शिकायत सुनाई पड़ने के कारण भट्टाचार्य ने पहली सितम्बर को घोषणा की कि रडन स्क्वैयर के अलावा कलकत्ता के और किसी पार्क में व्यवसाय केंद्र नहीं बनेगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हावड़ा बेलीलियस पार्क के मामले में जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कलकत्ता में कुल १८६ बड़े पार्क हैं। सी०आई० टी० के पार्कों को शामिल करने पर उनकी संख्या २१० होती है। कलकत्ता कार्पोरेशन चाहे भी तो उनकी देखरेख नहीं कर सकता। इसलिए हम मध्य कलकत्ता के १५ पार्कों की सजावट और देखरेख का काम एक गैरसरकारी संस्था को सौंपने जा रहे हैं। अन्य १८ पार्कों की सजावट के लिए हम व्यावसायिक संस्थाओं से बातचीत करने में लगे हैं। स्थानीय निकाय मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह जो कहा कि हम और किसी पार्क में व्यावसायिक केंद्र बनने नहीं देंगे, इसे पत्रकार लोग ज्योति बसु की बड़ी हार मानने लगे हैं। प्रसिद्ध पत्रकार तापस गंगोपाध्याय को तो इसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य गुट और ज्योति बसु गुट के बीच ठंडी लड़ाई के लक्षण दिखायी पड़ने लगे हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेख करना जरूरी है कि कार्पोरेशन ने दक्षिण कलकत्ता के तिकोनिया पार्क में शरत समिति को जमीन देने का जो प्रस्ताव किया था, उसे बुद्धदेव बाबू ने स्थानीय निकाय मंत्री की हैसियत से रद्द कर दिया है।

रडन स्क्वैयर विवाद सी० पी० एम० की पोलितब्यूरो तक भी पहुंचा है। १६ सितम्बर को सी०पी०एम० पोलितब्यूरो के नेता बी०टी० रणदिवे त्रिपुरा से कलकत्ता आये और रडन स्क्वैयर संबंधी रिपोर्ट लेकर दिल्ली गये। इसके पहले दूसरे सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत ने राज्य कमेटी से रडन स्क्वैयर संबंधी रिपोर्ट मांगी थी।

भ्रष्टाचार के आरोपों का भविष्य: यदि कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो वह कभी अपने पीछे निश्चित प्रमाण नहीं छोड़ता। काले धन का लेन-देन चोर दरवाजे से होता है, जिसे सामान्य लोग शायद ही देख पाते हैं। लेकिन दो केंद्रीय मंत्री अजित पांजा और प्रियरंजन दासमुंशी ने जो विधानसभा की सर्वदलीय जांच समिति गठित करने की बात कही है, वह विशेष महत्व रखती है। प्रियरंजन बाबू ने साफ कहा है कि इन सारे भ्रष्टाचारों के पीछे मुख्यमंत्री ज्योति बसु हैं। इसलिए उनको इन आरोपों से बाहर रहने के लिए विधानमंडलीय जांच समिति द्वारा इनकी जांच करानी पड़ेगी। भले ही उस जांच समिति में वाम मोर्चे के सदस्य अधिक रहें और उसका अध्यक्ष भी सी०पी०एम० का बने, फिर भी जांच तो हो। दूसरी तरफ साल्टलेक में भूमि आवंटन संबंधी आरोपों की जांच उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश से कराने की बात प्रियरंजन बाबू ने कही है। भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि मुख्यमंत्री जांच समिति गठित करने की मांग को स्वीकार करते हैं या नहीं। उसके पहले तक चटपटी अफवाहों का बाजार गरम रहेगा।

—विशेष प्रतिनिधि

अब बाकी सभी सिंथेटिक इनैमल इसके आगे फीके पड़ जाते हैं

पेश है

गारकोट

सुपरग्लॉस

सिंथेटिक इनैमल

अब, गरवारे पेण्ट्स प्रस्तुत करते हैं गारकोट सुपरग्लॉस. एक बिल्कुल ही नया, टिकाऊ और चमकीला सिंथेटिक इनैमल. इसके आगे बाकी सभी इनैमल फीके पड़ जाते हैं.

क्या खूब टिकाऊ.

इसकी एक पतली-सी परत सतह पर फैलकर बरसों उसकी रक्षा करती है. न झुर्रियाँ पड़ें, न छिलके उभरें–मौसम चाहे कितना ही बेरहम क्यों न हो.

क्या खूब चमकीला.

यह सतह को एक ऐसी खूबसूरत चमक देता है जो समय के साथ न तो फीकी पड़ती है, न रंग बदलती है.

ब्रिलियंट व्हाइट, ग्लो व्हाइट और ब्लैक समेत तरह-तरह के ४० आकर्षक रंग-छटाओं में से चुनिए.

दूसरी रंग-छटाएं तैयार करने के लिए गारटिंट यूनिवर्सल स्टेइनर भी मिलता है.

GARCOAT
SUPERGLOSS
SYNTHETIC ENAMEL
Garware Paints
Signal Red

GARWARE
गरवारे

गरवारे पेण्ट्स लिमिटेड का
एक उत्कृष्ट उत्पादन

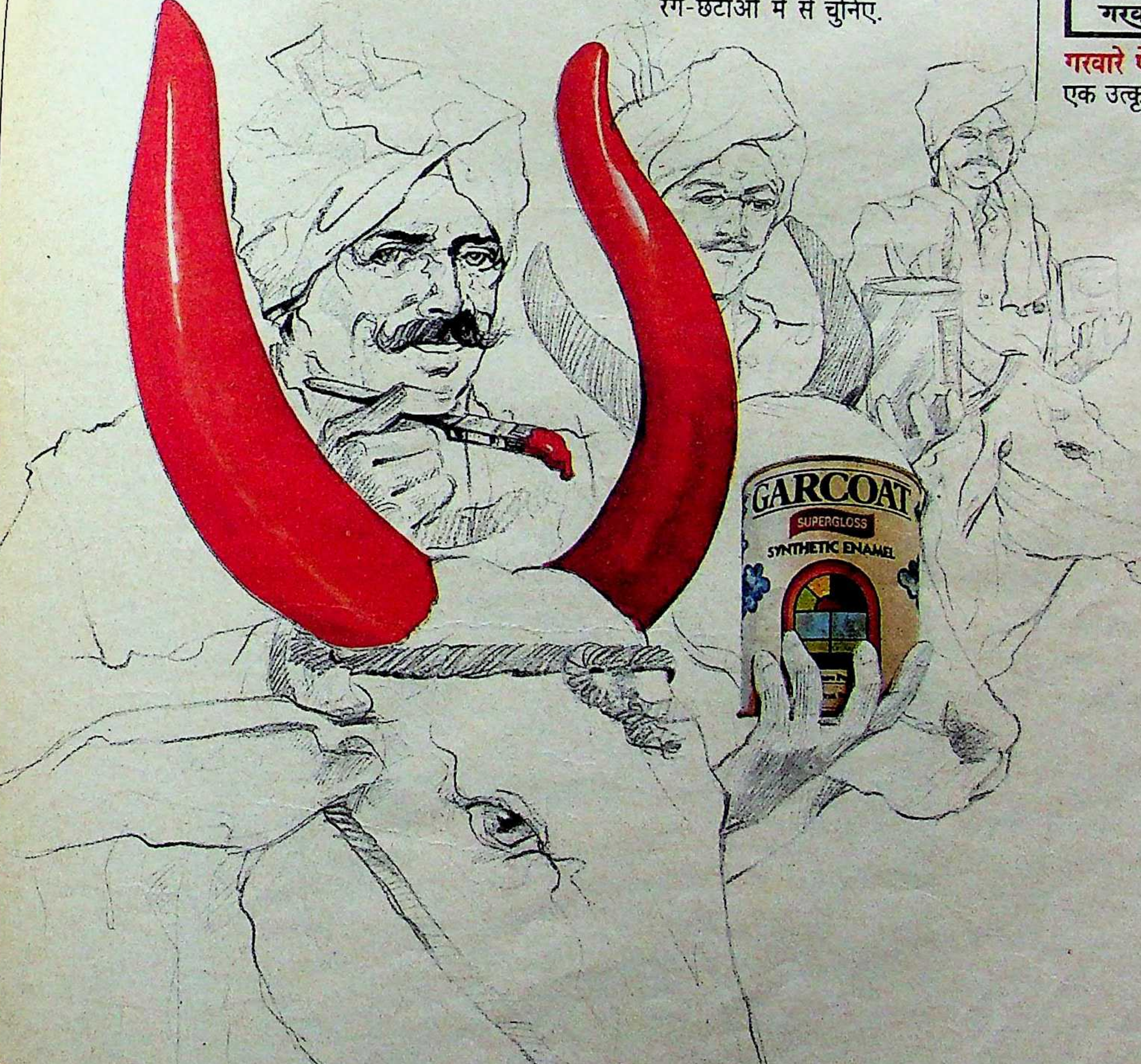
GARCOAT
SUPERGLOSS
SYNTHETIC ENAMEL

R K SWAMY/GPL3243/HN

इतना टिकाऊ, हमेशा नए का नया. इतना चमकीला, पड़े न कभी फीका.

डिंपल कपाड़िया

श्रीदेवी व स्मिता का नया विकल्प

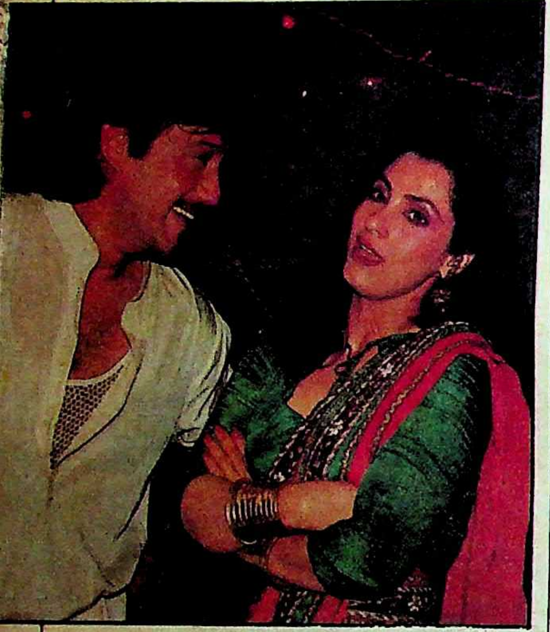

जैकी श्राफ और डिंपल

छाया: दुर्गा प्रसाद

बारह वर्ष पहले जब 'बाबी' प्रदर्शित हुई, तो सभी ने एक स्वर से यह फतवा दे दिया था कि नरगिस की असली वारिस फिल्म उद्योग में आ गयी—उसमें नरगिस जैसा सौंदर्य भी है और ग्लैमर भी। उसे सहज ही 'नंबर वन' अभिनेत्री मान लेनेवाले लाखों-करोड़ों दर्शकों को अचानक उसके विवाह करके फिल्मों से संन्यास ले लेने के कारण काफी सदमा पहुंचा। अब 'इंसाफ' और 'काश' जैसी फिल्मों की सफलता ने पुनः उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जिसका रास्ता सीधे 'नंबर वन' को जाता है। उसे अब श्रीदेवी और स्मिता पाटील का विकल्प मान लिया गया है—उसमें ग्लैमर और खूबसूरती भी है और चरित्र को जीने की कसक भी जो एक साथ किसी भी अभिनेत्री में इस समय नहीं है।

जयपुर का होटल जयमहल। रात में, शूटिंग से वापस आये सितारे धर्मेन्द्र के कमरे में स्कॉच और कहकहों के सहारे दिनभर की थकान उतार रहे हैं। फिर जल्दी सोने चले जाते हैं कि सुबह ही उठकर शूटिंग की तैयारी करनी है। लेकिन इस पार्टी से अलग एक अभिनेत्री अपने कमरे में बैठी संवाद याद

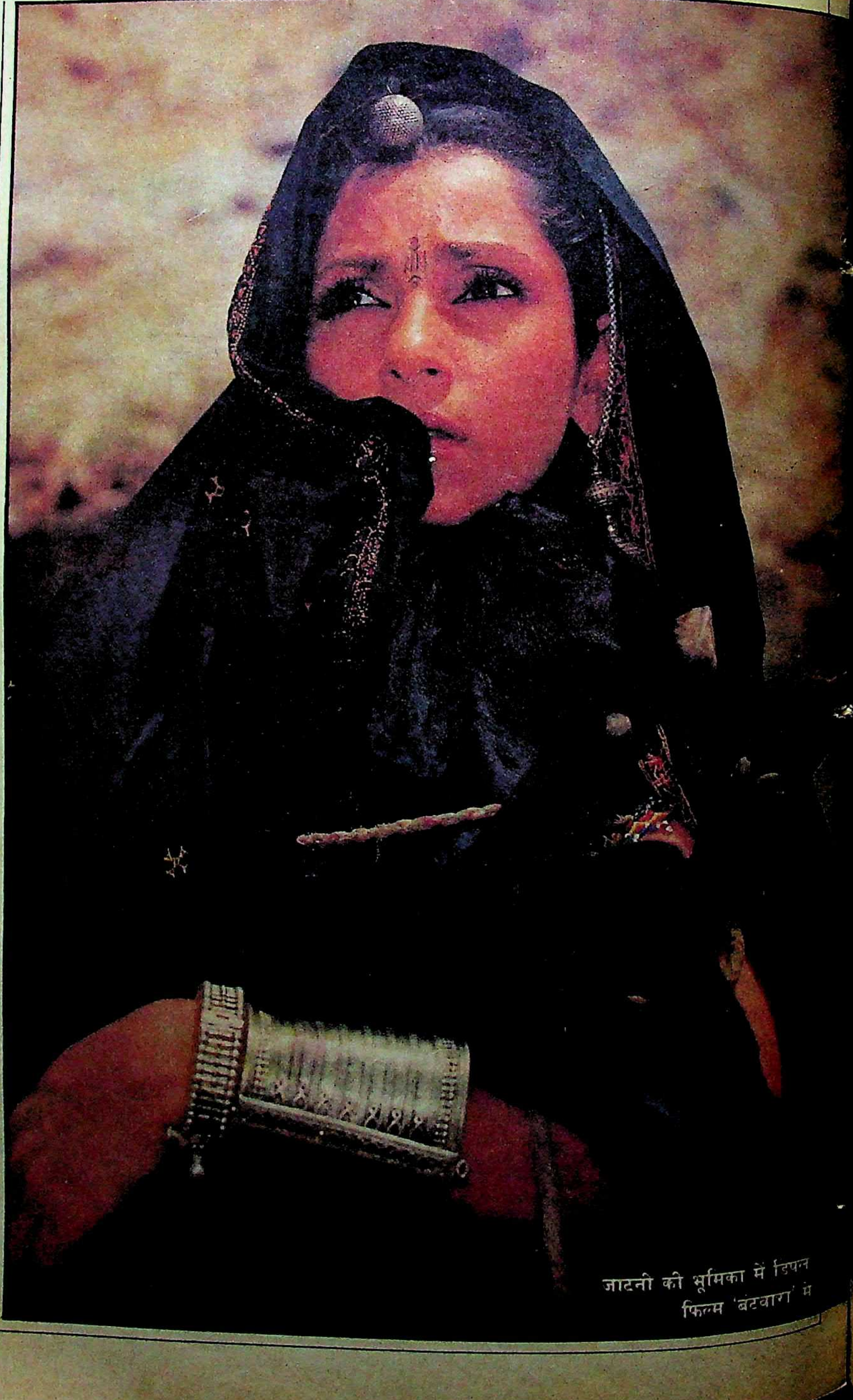

जाटनी की भूमिका में डिंपल फिल्म 'बंटवारा' में

कर रही है—कल होनेवाली शूटिंग का रिहर्सल कर रही है, 'अपोजिट कैरेक्टर' के रूप में सामने खड़ी है—उसकी हेयर ड्रेसर। उस पंचसितारे होटल की खिड़कियों पर एक-एक कर, कमरों में बंद होती रोशनियों के साथ अंधेरा छाने लगता है, लेकिन उस अभिनेत्री के कमरे की खिड़कियों से रोशनियों की जगमगाहट अभी भी बाहर फैल रही है। हेयर ड्रेसर जम्हाई को रोकने के लिए बार-बार हाथ मुंह पर ले जाती है, लेकिन हर बार वह "थोड़ा ठहर, बस दो डायलाग और, कल का शॉट बड़ा चैलेंजिंग है," कहकर उसे सोने जाने से रोक देती है।

और दूसरे दिन पहला ही टेक ओ०के० हो जाता है, तो सभी उसे घेर लेते हैं। बधाइयों का दौर शुरू हो जाता है। "अरे तुम तो बिलकुल जाटनी लग रही थी, वही आवाज वही टोन और एकदम वही लुक!" धर्मेन्द्र उस अभिनेत्री की पीठ थपथपाता है, "कहां से किया इतना नेचुरल ऑब्जरवेशन?"

छाया: दुर्गा प्रसाद

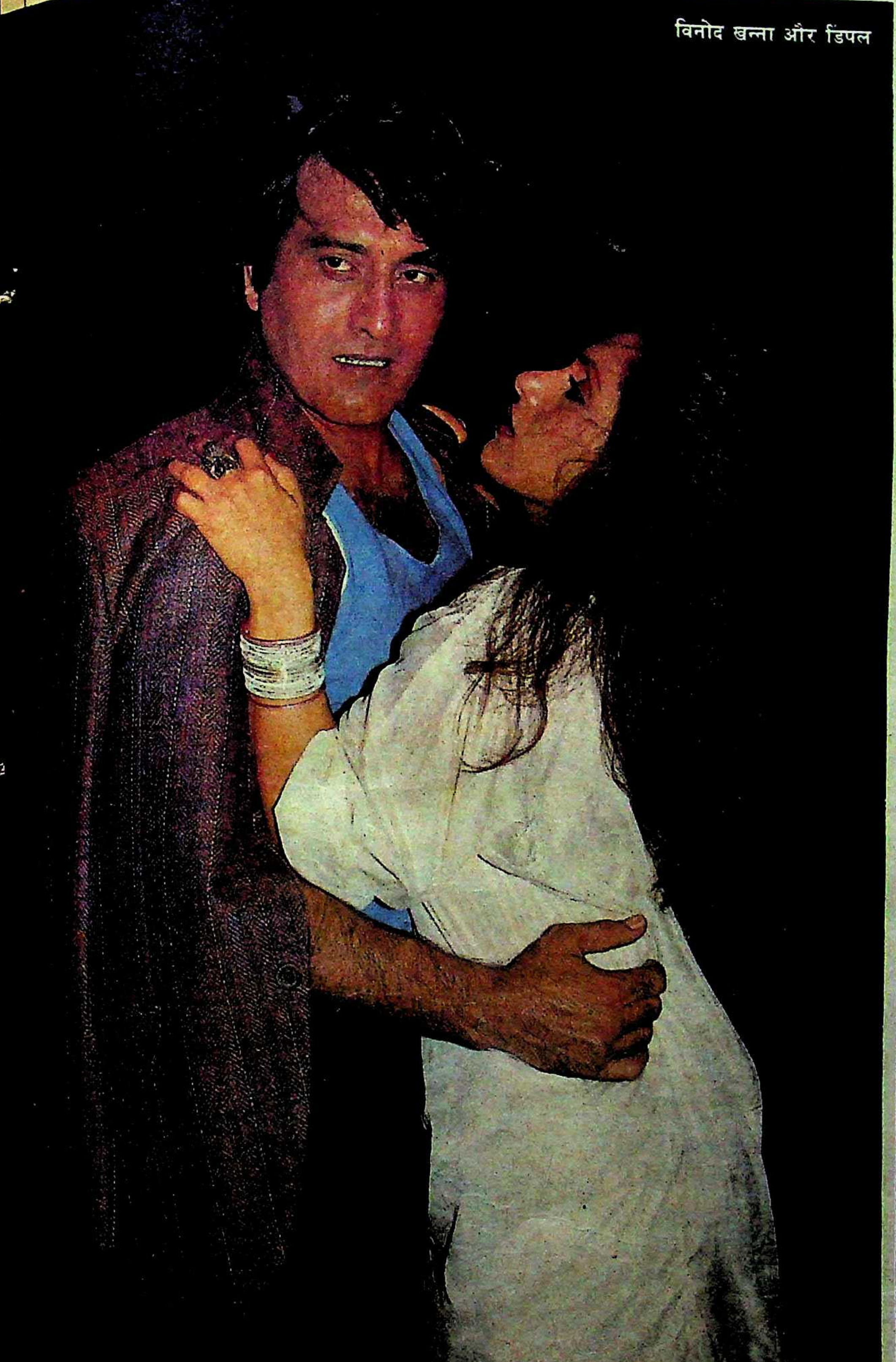

विनोद खन्ना और डिंपल

दस्यु सुंदरी की भूमिका में डिंपल: फिल्म 'महावीरा' में

"जब शूटिंग के बाद आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होते थे, मैडम पास के गांवों में जाकर वहां की औरतों से मिलकर बात करती थीं।" जवाब उस अभिनेत्री—डिंपल कपाड़िया की जगह, उस हेयर ड्रेसर देती है, "वहां की औरतों के साथ बैठकर घंटों बातचीत करती हैं, उनके चलने-फिरने की स्टाइल को ऑब्जर्व करतीं, फिर वापस होटल आकर रात में रिहर्सल करती थीं।"

इतना ही नहीं, फिल्म 'बंटवारा,' जिसमें डिंपल नायिका की भूमिका निभा रही थी, के निर्माण-नियंत्रक का कहना था, "डिंपल ने गांवों में घूम-घूम कर वहां की महिलाओं के आभूषण और कपड़े देखे तथा हूबहू वैसे ही अपने खर्च से बनवाये। कुछ औरतों से तो उन्होंने उनके ट्रेडीशनल कास्ट्यूम और आभूषण असली कीमत से दुगने रुपए देकर खरीद लिये। हमारी एक फिल्म में (कयामत) स्मिता पाटील ने काम किया था, उनकी भूमिका काफी छोटी थी, लेकिन जो इन्वाल्वमेंट मैंने उनमें देखा था, वही डिंपल में देखा। आनेवाले वर्षों में डिंपल अगर स्मिता पाटील की जगह ले ले, तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं तो समझता हूं इस समय वह अकेली अभिनेत्री है जो 'नंबर वन' बन सकती है और अगर ऐसा हुआ, तो शायद नरगिसजी के बाद वह पहली 'नंबर वन' अभिनेत्री होगी, जो स्टार के साथ-साथ एक्ट्रेस भी है। इनके अलावा तो शेष सिर्फ स्टार रहीं।"

Cavanders
Gold Leaf
STATUTORY WARNING:
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
Cavanders
GOLD LEAF
Cavanders
Gold Leaf

सोने सा खरा स्वाद जिसका न कोई जवाब

कैवंडर्स
गोल्ड लीफ

वैधानिक चेतावनी: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

everest/487/HHA/341 hin

सफलता : 'इंसानियत के दुश्मन' और 'इंसाफ' की सफलता ने डिंपल के अंधेरे में पड़े कैरियर को न केवल उजास और सफलता की चकाचौंध से भर दिया, बल्कि 'नंबर वन' श्रीदेवी तथा स्व० स्मिता पाटील के विकल्प के रूप में उसे आगे ला खड़ा किया है। एक तरफ उसने जे०पी० दत्ता और महेश भट्ट की फिल्मों में काम करने के लिए अपनी 'प्राइस' और 'शर्तों' को ताक पर रख दिया है, तो दूसरी तरफ मनमोहन देसाई से लेकर के० भाग्यराजा तक हर बड़े निर्देशक डिंपल को लेकर फिल्में बनाने के लिए लालायित हैं।

आज डिंपल के सामने दो पीढ़ियों की चुनौती है। एक तरफ श्रीदेवी, रेखा, जयाप्रदा, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो, भानुप्रिया जैसी पूर्व स्थापित अभिनेत्रियां हैं, तो दूसरी तरफ नीलम, फरहा, किमी काटकर, मंदाकिनी, माधवी, माधुरी दीक्षित स्वप्ना जैसी नयी अभिनेत्रियों की लंबी कतार। एक तरफ ग्लैमर का अछोर विस्तार, तो दूसरी तरफ बाक्स आफिस का तिलिस्म। और एक लंबे अर्से के उपरांत वापसी के बाद डिंपल इन सबका कड़वा जायका ले चुकी है। 'सागर,' 'जख्मी शेर' आदि शुरुआत की अपनी हर फिल्म में उसने सेक्स तथा अंग प्रदर्शन के हर हथियार को बाक्स आफिस पर सफलता के लिए आजमाया और हर वार खाली गया।

लंबी असफलता के वाद डिंपल को अहसास हुआ, उसकी खुद की 'बाबी' या श्रीदेवी, रेखा, जयाप्रदा की सफलता का कारण उनका ग्लैमर नहीं, अभिनय था। उनकी अंग-प्रदर्शन वाली फिल्में बाक्स आफिस पर पिट गयीं और श्रेष्ठतम अभिनयवाली फिल्मों ने उन्हें सफलता भी दी और लोकप्रियता भी। डिंपल ने अपनी 'नीति' में परिवर्तन कर दिया। फलत: श्रीदेवी की 'प्राइस' और 'डेटों' से निराश फिल्म निर्माता डिंपल की ओर रुख करने लगे और देखते-देखते उसने इतनी फिल्में अनुबंधित कर लीं कि पांच वर्ष तक उसके स्टारडम को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरह से वह गंभीरता और निष्ठा के साथ अपनी भूमिकाओं के लिए मेहनत कर रही है—ग्लैमर और अभिनय के तालमेल को मिलाकर चल रही है, उसने उसके लिए 'नंबर वन' का द्वार खोल दिया है।

बाबी का तिलस्म : बारह साल पहले बंबई फिल्म उद्योग में डिंपल का उदय एक ऐसे सितारे की तरह हुआ, जिसे करोड़ों सिनेमा प्रेमी टकटकी बांध कर देखते रह गये। 'बाबी' फिल्म में उसकी अभिनय शैली को राज कपूर ने जो कवित्वमय रूप दिया, वह महान अभिनेत्री नरगिस का पर्याय लगता था। वैसे समय में, जब अभिनेत्रियों की एक समूची पीढ़ी (मुमताज, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, सायरा बानो, नंदा, आशा पारेख) अस्त होने को थी, डिंपल का उदय फिल्म उद्योग के लिए बहुत ही शुभ था। तेरह साल की वह किशोर डिंपल 'बाबी' फिल्म रिलीज होने तक पंद्रह साल पूरे कर चुकी थी और उसके सामने सर्वोच्च अभिनेत्री का ताज रखा हुआ था। करोड़ों सिनेमा दर्शक उसकी दूसरी फिल्म की

हर तरह की भूमिका : माधवी के साथ कीचड़ युद्ध में डिंपल

एक भाव भंगिमा : डिंपल फिल्म 'बंटवारा' में

जाटनी का रूप : धर्मेंद्र के साथ फिल्म 'बंटवारा' में

साक्षात्कार/डिंपल कपाड़िया

मैं फिर से शादी करूंगी

इस बात को पांच साल हुए होंगे। खोयी-खोयी सी उदास डिंपल को उसके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया के जुहू स्थित बंगले में बैठी दूर समंदर को एकटक निहारते मैंने पाया था। तब मुझे लगा था जैसे उसके मन में छायी उदासी की परछाई बंगले की दीवारों, लान की हरियाली और समुद्र तट पर पड़ी सूखी रेत से होती हुई, दूर सागर तक फैल गयी है।...और, अब जैसे हर तरफ उसकी हंसी छिटकी हुई थी। उसके पिता चुन्नी भाई का बंगला 'रिनोवेट' किया जा चुका था और बहुत ही आकर्षक और नया लग रहा था—डिपल की नयी जिंदगी की तरह। 'माया' की तरफ से पूछे जाने वाले हर सवाल के लिए वह तैयार थी। सवालों का सिलसिला यों शुरू हुआ :

माया : दस साल पहले 'बाबी' में किये गये उन्मुक्त अभिनय को 'सागर' फिल्म में दोहराते वक्त, बदली मानसिक स्थितियों और परिस्थितियों का कितना प्रभाव रहा?

डिपल : बहुत प्रभाव रहा। 'बाबी' में मैं जो भूमिका कर रही थी, वह मेरी उम्र, उस उम्र में सोचने समझने के तरीकों से मेल खाती थी। मेरी 'नर्वसनेस' भी राज साहब (निर्देशक राजकपूर) को मेरे अभिनय का हिस्सा लगी। मगर दस साल बाद जब मैं फिर से कैमरा के सामने खड़ी हुई, तो मैं एक प्रौढ़ स्त्री थी, दो बच्चों की मां थी और अपने भविष्य के प्रति चिंतित थी। मेरी 'नर्वसनेस' मेरे अभिनय में सबसे बड़ी बाधा थी। इसलिए शुरुआत में निर्देशक रमेश सिप्पी को बहुत मेहनत करनी पड़ी और एक-एक 'शाट' की टेकिंग उन्हें दर्जनों बार करनी पड़ी। लेकिन मैंने भी कम मेहनत नहीं की। धीमे-धीमे 'सागर' की मारिया का 'करेक्टर' मुझमें घुल-मिल गया और मैंने उसे जैसा निर्देशक चाहता था, वैसा उतार दिया।

माया : मगर 'सागर' फिल्म टिकट खिड़की पर मामूली रही। यही हाल 'मंजिल-मंजिल,' 'जख्मी शेर,' 'लावा' और 'एतबार' जैसी फिल्मों का रहा।

डिंपल : 'सागर' फिल्म का एक गाना ही तब 'पिक्चराइज' हुआ था कि आगे की शूटिंग में महीनों लग गये थे। इस बीच मैंने, जो भी फिल्मी प्रस्ताव मेरे सामने आया, उसे स्वीकार कर लिया। नासिर हुसैन की फिल्म में काम करना कोई कम इज्जत की बात न थी। इसके अलावा मैंने दक्षिण की भी कुछ बहुत ही महत्वहीन फिल्मों में काम करना मंजूर कर लिया, जैसे 'पाताल भैरवी'। इन फिल्मों मे काम करने का सबसे बड़ा फायदा था अच्छे-से-अच्छा पैसा मिलना जो उस वक्त मेरी बहुत बड़ी जरूरत थी। साथ ही इन फिल्मों में काम करना मेरे तजुर्बे के लिए भी बहुत जरूरी था। रहा फिल्मों का चलना न चलना, तो मेरे लिए यही बहुत था। ये सभी फिल्में उतनी जरूर चलीं कि निर्माताओं को घाटा नहीं हुआ।

माया : 'अर्जुन' 'जांबाज' और फिर 'अल्लारखा' जैसी फिल्में 'फ्लाप' हो गयीं। क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि किसी भी फिल्म को स्वीकार करते वक्त अपनी भूमिका और फिल्म कहानी की जांच परख करनी चाहिए?

डिपल : क्यों नहीं। मगर अंतिम निर्णय तो 'पब्लिक' के हाथ में होता है। यदि 'पब्लिक' का निर्णय किसी को भी पहले मालूम हो जाये, तो 'फ्लाप' फिल्में बनें ही क्यों? यह तो पब्लिक की पसंद का सवाल है, जिसे कोई

पहले से नहीं भांप सकता कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। मैं भी यह निर्णय नहीं ले सकती। मैं ऐसी कौन सी भूमिका करूं जो लोगों को पसंद आ जाये। 'इंसानियत के दुश्मन' फिल्म में मैंने जो भूमिका की, वह मुझे खास पसंद नहीं थी। खासकर इस फिल्म में मैंने एक नृत्य किया जो सचमुच मेरे लायक न था। उसे देखते हुए खुद मुझे शर्म आती थी। मगर मेरा वह 'नाच' इतना हिट गया कि लोग कभी तालियां बजाते, तो कभी सीटियां। मेरी इस फिल्म में की गयी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आयी। इसका प्रमाण है मेरी 'फैन मेल'। इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार कोहली ने मुझे समझाया था कि किसी भी जज्बात का इजहार खुलकर करना बहुत जरूरी है। 'ओवर एक्टिंग' का सहारा लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। तबसे मेरी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गयी कि निर्देशक की राय मानना किसी भी कलाकार के लिए जरूरी है। मेरे अभिनय में जो कमियां थीं, वे मेरी समझ में आ गयीं। 'काश' फिल्म में आपने देखा होगा: एक—जब हीरोइन को मालूम पड़ता है कि उसके बच्चे को कैंसर है, दूसरे— जब वह अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने पूर्व पति के साथ पहाड़ों में घूम रही होती है, तो उसका प्रेमी विवाह की तारीख तय करने की बात करता है। इन दोनों स्थितियों में निर्देशक महेश भट्ट ने मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया। मैंने तब न तो यह परवाह की कि मैं जरूरत से ज्यादा 'लाउड' हो रही हूं, न यह सोचा कि मैं 'ओवर एक्टिंग' कर रही हूं। बल्कि अपने भीतर के 'इमोशन' का जितना जोरों से हो सकता था, धमाका किया। मेरे ये दो 'सीन' महेश भट्ट ने ओके कर दिये—मेरे लिए खुशी की बात थी। 'काश' के ये दृश्य बाद में पब्लिक को बहुत पसंद आये...।

माया: 'काश' की कहानी आपके वास्तविक जीवन से मिलती-जुलती है, ऐसा अकसर कहा जा रहा है?

डिंपल: बात सही है। एक 'सुपर स्टार' जब नीचे आने लगता है, उसकी क्या मानसिक स्थिति होती है, यह मैंने बखूबी देखा है। उसकी बीवी के रूप में उसके गुस्से और शक को झेला भी है। फिल्म में ऐसी स्थितियां मौजूद थीं जो मेरे जीवन में घटित हुई थीं। इसलिए मैं 'काश' की 'पूजा' के किरदार के साथ पूरी तरह घुलमिल गयी। निर्देशक महेश भट्ट ने यह बखूबी जान लिया कि मैं कहां किन दृश्यों में अपनी तरफ से 'कंट्रीब्यूट' कर सकती हूं। उन्होंने इसकी छूट दे दी। सचमुच कमाल के डायरेक्टर हैं महेश भट्ट...।उनसे मैंने बहुत सीखा और ऐसा आत्मविश्वास पाया जो हमेशा मुझमें बना रहेगा।

माया: फिल्मों में अब आपकी स्थिति 'स्टार' श्रेणी की हो गयी है।

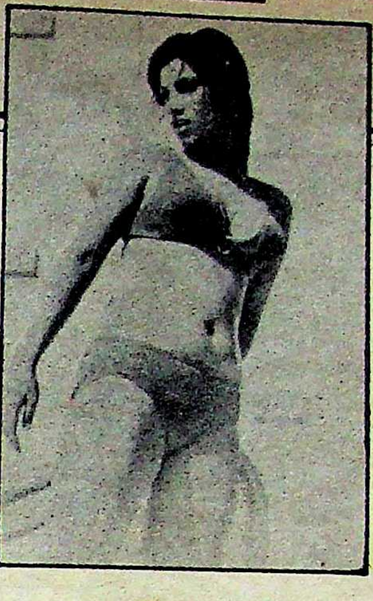

आज की बात और है-मैं जिसे प्यार करती हूं, वह भी मुझे प्यार करता है। कल भले ही कुछ हो, मगर ये क्षण मेरी जिंदगी के वाकई ऐसे हैं, जिनके लिए मैं सालों तरस गयी...।

डिंपल: बिलकुल। लेकिन 'स्टार्स' की तरह व्यवहार करना मुझे पसंद नहीं। खासकर निर्माता-निर्देशकों को मैं इस वजह से परेशान नहीं करना चाहती कि मैं स्टार हूं, तो उन्हें मेरी यह मांग पूरी करनी चाहिए, वह मांग पूरी करनी चाहिए वगैरह-वगैरह। मैं हर हाल में अपने आपको 'एडजस्ट' करना चाहती हूं। अपने पति का बंगला छोड़कर जब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर आयी, तो बंगले की मरम्मत हो रही थी। मुझे मेरे माता-पिता, भाई-बहनों, दोनों बच्चों और यहां तक कि नौकरानियों के साथ एक ही कमरे में 'हफ्तों' सोना पड़ा। इस ढंग के रहने-सहने में मुझे रत्ती भर की आपत्ति नहीं हुई। मैं 'स्टार' बनने की बात को बहुत ही स्वाभाविक बात मानती हूं। मुझे जैसे जिंदगी में दुख-सुख जैसी चीजें मिलीं, वैसे ही यह 'स्टार' की पदवी भी मिली है। 'स्टारडम' कितनी खतरनाक चीज है, यह मैं अपने पति के घर मे बहुत अच्छी तरह देख चुकी हूं। अपनी हर फिल्म के लिए टिकट खिड़की में हुए 'कलेक्शन' पर नजर रखना और ऐसे 'चमचों' से घिरे रहना जो हर बात पर तारीफ के पुल बांधते रहें और हर गलत को सही साबित करते रहें—किसी भी 'स्टार' के लिए कितनी घातक बात हो सकती है। मुझे 'स्टार' की ऐसी 'लाइफ स्टाइल' (जीवन शैली) से सख्त परहेज है। मैं बिलकुल स्वाभाविक जीवन जीना चाहती हूं।

माया: क्या इस बात से आपको इनकार है कि आपके जीवन में एक ऐसे साथी का प्रवेश हो चुका है जो आपका जीवन साथी भी बन सकता है?

डिंपल: नो...मुझे इस बात से कतई इनकार नहीं। मैं किसी को चाहने लगी हूं। इस बात से भी इनकार नहीं है, आगे चल कर मैं उससे शादी करूं। वाकई प्यार बड़ी गहरायी से महसूस करने की चीज है। मैंने तब राजेश खन्ना को प्यार किया था। मगर अब सोचती हूं, वह प्यार नहीं था। एक 'आबसेशन' था। राजेश खन्ना को मैंने परदे पर देखा—'सुपर स्टार' के रूप में उसके चारों ओर जो भी था, बहुत ही सुनहरा था। उसके शादी के प्रस्ताव के आने पर कुरबान हो जाने जैसी भावना से मैंने काम लिया। यह मुझे बाद में पता लगा कि प्यार करने के साथ यह भी जरूरी है कि प्यार पाया जाये। मगर मुझे प्यार कभी नहीं मिला। आज की बात और है—मैं जिसे प्यार करती हूं, वह भी मुझे प्यार करता है। कल भले ही कुछ हो, मगर ये क्षण मेरी जिंदगी के वाकई ऐसे हैं, जिनके लिए मैं सालों तरस गयी...।

माया: और, जो दो पुत्रियों का दायित्व यानी मां की भूमिका आपको निभानी है?

डिंपल: मेरी दोनों बेटियां ट्विंकल और चिंकी अब सयानी हो चुकी हैं। दोनों ने जिंदगी का वह अंधेरा पहलू देखा है जो मैंने अपने पति के घर में बिताया। वे दोनों मेरी बेटियां ही नहीं, मेरी सच्ची दोस्त भी हैं। मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं छिपायी। मेरे बारे में वे सब जानती हैं और उन्हें पता है कि भावनात्मक स्तर पर मुझ जैसी भीतर से टूटी औरत को प्यार चाहिए। उन्हें अपनी मां को खुश देखना हर हाल में पसंद है।

माया: आपके बारे में पत्र-पत्रिकाओं में जो रोमांटिक किस्से छपते हैं, उनका दोनों बच्चियों पर असर नहीं होता?

डिंपल: बिलकुल नहीं, दोनों अपनी मां को अच्छी तरह पहचानती हैं। 'स्टार' के साथ अफवाहें कैसे जोड़ी जाती हैं, इतना तो उनकी समझ में आ ही गया है। विनोद खन्ना, सनी देवल या कोई भी नाम उन्हें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वे बखूबी जानती हैं, उनकी मां की 'इमोशनल फीलिंग' कहां किसके साथ जुड़ी हैं। मेरे बीते दिन बहुत कड़वे रहे, दर्दनाक रहे, मगर मेरा आज बहुत सुंदर है। इस 'आज' में मैं जीना चाहती हूं, एक-एक लमहा बेहतर और खूबसूरत बनाना चाहती हूं। मैंने कहा न मैं आज भी बीवी बनने को तैयार हूं, क्योंकि अब यह पहले जैसी गलती नहीं। सोचं-समझ कर उठाया गया कदम होगा।

—हरीश तिवारी

प्रतीक्षा में आंखें बिछाये हुए थे।

और यही समय था, जब नये अभिनेता राजेश खन्ना के लिए पहली बार फिल्म उद्योग में 'सुपर स्टार' जैसा शब्द ईजाद हुआ और उसकी अभिनय प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व ने जादू जैसा चमत्कार करना शुरू कर दिया। फिल्म उद्योग और दर्शक सब जैसे उसके दीवाने हो उठे।

प्रसिद्ध संगीतकार स्व० मदनमोहन की भांजी अंजू महेन्द्रू, जो थियेटर के दिनो से राजेश खन्ना के संपर्क में थी, उन दिनों बिन ब्याही पत्नी के रूप में राजेश खन्ना के साथ रहती थी। उसके घर की व्यवस्था भी अंजू स्वयं करती थी और यह लगभग तय हो चुका था कि शीघ्र ही उसकी अवैध पत्नी की भूमिका वैध हो जायेगी। अंजू इस बात से भी आश्वस्त थी कि काका (राजेश खन्ना) अब उसके अलावा दूसरी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। पर इधर 'बाबी' प्रदर्शन के लिए तैयार थी और उधर राजेश खन्ना के हृदय में डिंपल घर बना रही थी। 'बाबी' प्रदर्शित हुई और डिंपल तथा राजेश खन्ना परिणय सूत्र में बंध गये।

इधर अंजू राजेश खन्ना के साथ परिणय सूत्र में बंधने के सपने संजो रही थी, तो उधर काका जबरदस्ती गले पड़ गयी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब अपने दोस्तों के साथ सोच रहे थे। दोस्तों ने राय दी—अंजू को हटाने का एक ही रास्ता है, काका किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले। इस तरकीब से अंजू खुद-ब-खुद काका का घर छोड़ कर चली जायेगी।

देश भर की पत्र-पत्रिकाओं में फिर राजेश खन्ना और डिंपल के विवाह का बहुत ही जोरदार, बहुत ही रंगीन धमाका हुआ। तकदीरवाली निकली डिंपल—राजेश खन्ना जैसा सुपर स्टार उसे पति के रूप में मिला और पहली ही फिल्म में उसे श्रेष्ठ अभिनेत्री का 'फिल्म फेयर' पुरस्कार मिला। अब लोगों को प्रतीक्षा थी, ऐसी फिल्मों की, जिसमें दोनों पति-पत्नी हीरो-हीरोइन के रूप में दिखायी दें।

मगर दोनों की असल जिंदगी का 'स्क्रीन प्ले' इस ढंग से लिखा गया था कि अचानक दोनों सितारों को राहु ने डस लिया। शादी के बाद से राजेश खन्ना की फिल्में दिन-ब-दिन दुर्गति पाती चली गयीं और डिंपल का सितारा घरेलू कलह के दलदल में धंसता चला गया।

शादी के महीने भर बाद की बात है, संगीतकार मदनमोहन के पैडर रोड स्थित फ्लैट पर मेरी मुलाकात अंजू से हुई थी, तब उसने जो कहा था, मुझे आज तक याद है—'मेरे साथ उसने (राजेश खन्ना) बहुत बड़ा धोखा किया...उस वक्त तो सचमुच मैंने आत्महत्या करने की ठान ली थी...लेकिन अब सोचती हूं जो भी हुआ वह मेरे हक में अच्छा ही हुआ। 'नेचर' से काका 'सैडिस्ट' है। दूसरे को दुखी करने और तड़पाने में उसे मजा आता है। कपाड़िया फैमिली उसकी 'सुपर स्टारी' के चक्कर में आ तो गयी, मगर बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा...बेचारी डिंपल कितनी 'इनासेंट' है...मुझे उससे पूरी हमदर्दी है...।"

और, शादी के नौ साल बाद चुन्नी भाई कपाड़िया के बंगले में मैं डिंपल से मिल रहा था। राजेश खन्ना का घर छोड़-छाड़ कर वह हमेशा के लिए अपने पिता के पास चली आयी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों में बेहद निराशा। वह जिस तरफ देखती थी, उसी तरफ देखती रह जाती, "फिल्मों में काम करूं या नहीं करूं, अभी मैं बिलकुल तय नहीं कर पायी हूं...पहले कुछ ठीक तो हो जाये...।" उसने तब कहा था।

यह ठीक होने से उसका मतलब क्या हो सकता था? क्या राजेश उसे फिर वापस ले जाने आ सकता था, "नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता..." डिंपल भावावेश में कह रही थी, "मैंने अब हमेशा के लिए फैसला कर लिया है, अब वापस नहीं लौटूंगी...।"

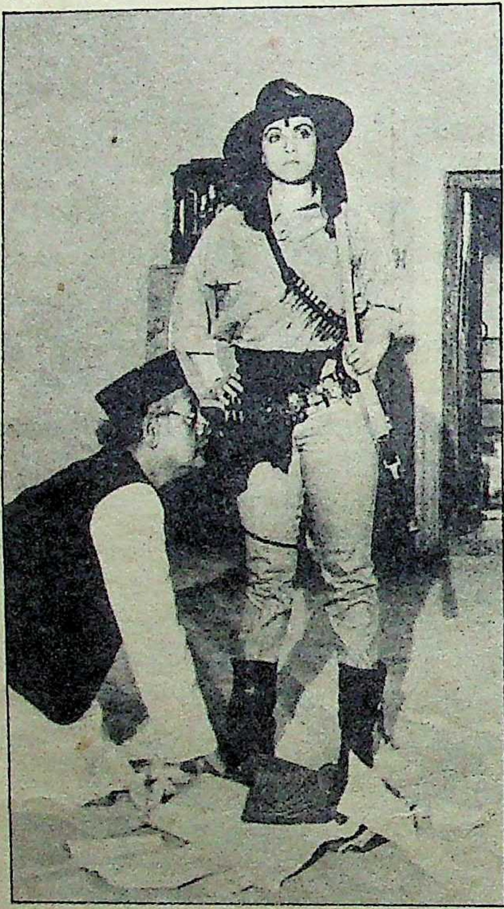

हसीन डकैत: डिंपल 'महावीरा' में

तो 'ठीक' हो जाने का मतलब था—तलाक। इसके बाद फिर से नये जीवन की शुरुआत। तब फिल्मों में हीरोइन बनने नित नयी लड़कियां आ रही थीं। दक्षिण की श्रीदेवी और जयाप्रदा अपनी जगह बना रही थीं और मीनाक्षी शेषाद्रि, अनिता राज, किमी काटकर, अमृता सिंह के साथ-साथ मंदाकिनी का नाम भी जोरों से उछल रहा था। डिंपल का हाल यह था कि उसका पति राजेश खन्ना खुद निर्माताओं से कहता फिर रहा था, 'बूढ़ी बाबी' को भला परदे पर देखने का साहस पब्लिक कैसे जुटा पायेगी।

दिन बहुरे: यह भी अजीब संयोग की बात थी, जैसे ही डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ा, दस सालों से बाक्स आफिस पर ठप्प पड़ा राजेश का नाम फिर चल पड़ा। 'सौतन' और 'अवतार' फिल्मों की सफलता ने फिर राजेश खन्ना की धाक फिल्म उद्योग में जमा दी। निर्माताओं का वह रेवड़, जो उसके पास फटकने में भी डरता था, फिर उसके इर्द-गिर्द मंडराने लगा। ऐसे समय में जब राजेश खन्ना किसी भी निर्माता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता था, डिंपल को फिल्म में लेने का साहस भला कौन कर सकता था?

राजेश खन्ना के कैंप से डिंपल के खिलाफ बाकायदा अभियान-सा चलाया जा रहा था कि डिंपल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। दो बच्चों की मां होने की वजह से उसकी 'इमेज' भी बिगड़ चुकी है और 'बाबी' जैसी मासूमियत का उसके चेहरे पर कोसों पता नहीं। उसको फिल्मों में लेना जान-बूझकर डूबना है।

लेकिन निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की आंखें भी किसी जौहरी से कम न थीं। उन्हें डिंपल में अब भी अभिनय का वह नूर नजर आ रहा था जो बखूबी चमक सकता था। 'सागर' फिल्म की कहानी उन्होंने डिंपल को ही ध्यान में रख कर लिखवायी और उसके साथ हीरो के रूप में दो मंजे हुए अभिनेताओं का चुनाव किया—ऋषि कपूर तथा कमल हासन।

डिंपल का कहना है—"तब फिल्म उद्योग में रमेश सिप्पी के लिए कहा जाने लगा, मुझ जैसी हीरोइन को लेकर वह गलती ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पागल होने का सबूत भी दे रहा है। लेकिन रमेश सिप्पी पर ऐसी बातों का रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा। फिल्म शुरू करने से पहले रमेश ने मेरा 'स्क्रीन टैस्ट' लेने का जो फैसला किया, उससे मैं इतना घबड़ा गयी कि आज भी बयान नहीं कर सकती। जब मेरा 'टैस्ट' लिया गया, मेरे पैर थरथरा रहे थे। पूरें दस सालों बाद मैं कैमरा के सामने खड़ी हुई थी सो आर्कलैंप की गरम रोशनी में मैं पसीना-पसीना हो उठी। मुझे लग रहा था, यह मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है, जिसमें मेरा पास होना बहुत ही मुश्किल है। भीतर आत्मविश्वास होता, तो बटोरती भी। लेकिन भीतर तो सब खाली-खाली था और अगर कुछ था, तो डर। मुझे इस डर पर विजय पानी थी जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी। खैर जैसे-तैसे मैंने 'स्क्रीन टैस्ट' दिया। बाद में इस 'स्क्रीन टैस्ट' के परिणाम बहुत ही निराशाजनक निकले। लोग रमेश को समझाने लगे। वह मुझे बदल कर दूसरी हीरोइन ले ले। रमेश सिप्पी जैसे निर्माता-निर्देशक की फिल्म में भला कौन हीरोइन काम करना नहीं चाहेगी? और, मुझे लगने लगा, अब मैं वाकई हीरोइन बनने के काबिल नहीं रही। मेरा आत्मविश्वास जैसे चूर-चूर हो गया था। आंखों के आगे अंधेरा-सा छाता नजर आ रहा था। अब इसके अलावा और कौन सा काम कर सकती हूं, सोच नहीं पा रही थी।"

कुछ देर रुक कर डिंपल बतलाती है, "लेकिन भले ही मेरा अपने आप पर से विश्वास उठ गया था, मगर रमेश का मुझ पर पूरा विश्वास था। 'सागर' फिल्म सैट पर पहुंच गयी। तब तक मैं बहुत हद तक

अपने आपको संभाल चुकी थी और काफी हिम्मत भी बटोर चुकी थी। एक लाइन का डायलाग मुझे बोलना था और इस एक लाइन के पूरे पच्चीस 'रिटेक' रमेश ने करवाये। मेरे हक में यह भी अच्छी बात हुई। हर बार पहले से बेहतर 'शाट' देने की कोशिश में मैं बजाय घबराने के और ज्यादा हिम्मत बटोरती चली गयी। और जब यह 'शाट' ओके हुआ, तो मैंने पाया मेरी सारी घबराहट, कैमरे के आगे का डर और हीन भावना जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गयी। बाद में 'सागर' फिल्म में की गयी मेरी भूमिका इतनी सराही गयी, मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला...।"

"सागर' ने डिंपल कपाड़िया को भले ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलवाया। मगर 'जख्मी शेर,' 'मंजिल-मंजिल,' 'पाताल भैरवी,' 'लावा,' 'एतबार,' जैसी आधा दर्जन फिल्मों ने बाक्स आफिस पर उसे वह पुरस्कार नहीं दिलवाया जो हर कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। 'सागर' फिल्म ने भी वह 'बिजनेस' नहीं किया जो 'शोले' जैसी फिल्म के निर्माता की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी था। लिहाजा फिर से शुरू किया गया डिंपल का फिल्म कैरियर लड़खड़ाने लगा। 'सागर' के चक्कर में उसने राज सिप्पी की 'सदमा' छोड़ दी थी, जो बाद में श्रीदेवी को मिली। और 'सदमा' ने श्रीदेवी के पांव बंबइया फिल्मी दुनिया में जमा दिये। संभवत: यह अफसोस भी डिंपल को कम नहीं हुआ होगा।

असफल फिल्मों का फिर दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें 'अर्जुन,' 'जांबाज' और 'अल्लारखा' जैसी फिल्में थीं। फिल्म उद्योग जैसा बेवफा उद्योग दूसरा कोई नहीं होगा। एक अदद सफलता यहां किसी भी हीरो या हीरोइन को आसमान पर चढ़ा देती है, तो असफलता खाक में मिला देती है। डिंपल की फिल्मों का पिटना और श्रीदेवी तथा जयाप्रदा की फिल्मों का चलना इस बात का सबूत था कि दर्शक जिस हीरोइन को चाहते हैं, उसकी ऊलजलूल फिल्म को भी चला देते हैं, जिसे नहीं चाहते, उसकी अच्छी-से-अच्छी फिल्म को चुटकियों में उड़ा देते हैं।

डिंपल की तरफ ध्यान न जाने की बात इसलिए भी पैदा हो रही थी कि मंदाकिनी, मीनाक्षी शेषाद्रि, स्वप्ना, किमी काटकर, माधवी, अनिता राज, जैसी अभिनेत्रियों के पास एक-एक अदद हिट फिल्म थी, जिसके बल पर जयाप्रदा और श्रीदेवी के बाद की बची-खुची फिल्में उनकी झोली में टपक रही थीं। बेचारी डिंपल अब हताश-सी नजर आने लगी।

उधर 'अवतार' की सफलता से राजेश खन्ना फिर से 'सुपर स्टार' बनने के जो सपने देख रहे थे, उनका भी मलीदा बन गया। रोमांटिक हीरो के रूप में वह दर्शकों को फूटी आंखों नहीं भाया। लिहाजा उसने राजनीति का दामन थाम लिया। इसी बीच उसकी जिंदगी से टीना मुनीम भी निकल गयी।

कैरियर में उछाल : डिंपल के डूबते कैरियर में उस वक्त जबरदस्त उछाल आया, जब अमिताभ बच्चन के साथ 'शहंशाह' फिल्म में उसके हीरोइन बनने की चर्चा फैली। हालांकि अमिताभ जैसे हीरो के साथ काम करने में कोई भी हीरोइन अपने आपको सौभाग्यशाली समझ सकती है, मगर डिंपल को बहुत ही लाचारी के साथ यह 'प्रपोजल' अस्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अमिताभ की तारीखों पर वह शूटिंग करने में असमर्थ थी। डिंपल ने वे तारीखें दूसरे निर्माताओं को पहले ही दे दी थीं। लिहाजा डिंपल अमिताभ की फिल्म में काम तो नहीं कर सकी, मगर फिल्म उद्योग में लोगों के मनों में यह धारणा जरूर बैठ गयी, वह ऐसी हीरोइन है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

महेश भट्ट, राज सिप्पी, राजकुमार कोहली, जे०पी० दत्ता जैसे निर्देशकों की जो हीरोइन हो, वह मामूली नहीं हो सकती। मगर बड़े निर्देशक, बड़ी हीरोइन, इनके बड़े होने का प्रमाण भी तो मिलना चाहिए। फिल्म चलनी भी तो चाहिए।

सन, '८६ का वर्ष शुरू क्या हुआ, डिंपल की फिल्में बाक्स आफिस पर अपनी सफलता का जादू दिखलाने लगीं। वर्ष के प्रारंभ में धर्मेन्द्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर जैसे दिग्गज 'स्टार्स' के साथ उसकी फिल्म रिलीज हुई—'इंसानियत के दुश्मन' जो खूब चली। इसी वर्ष 'सागर' फिल्म के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट ने एक साथ दो फिल्मों (काश व मार्ग) के लिए उसे अनुबंधित किया और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की भी उसकी चिरसंचित अभिलाषा पूरी हुई। टीनू आनंद के निर्देशन में बनने वाली 'आलीशान' में वह अमिताभ की हीरोइन होगी।

निराली अदा : डिंपल 'महावीरा' में

विनोद खन्ना की वापसी के बाद पहली फिल्म 'इंसाफ' की सफलता ने डिंपल को अचानक जयाप्रदा और श्रीदेवी की कतार में पहुंचा दिया है। इधर महेश भट्ट की 'काश' फिल्म में डिंपल ने जो भावनापूर्ण अभिनय किया है, उसने किन्हीं-किन्हीं दृश्यों में दर्शकों को हिला दिया है। यही कारण है, अब वितरकों की दुनिया में डिंपल ने ऐसी जगह बना ली, जहां वह अपनी शर्तें मनवा सकती है। 'हिट' फिल्म बनाने की तमन्ना हर निर्माता-निर्देशक की होती है, उसके लिए 'हिट' हीरोइन भी चाहिए। हिट हीरोइन यानी जिसे दर्शक लगातार तीन घंटों तक देखते रहें तो और भी देखने की इच्छा हो। डिंपल ऐसी ही हीरोइन है। और जब ऐसी हीरोइन के रूप में आम दर्शक उसे मान्यता दे चुके हैं, तो आगे आने वाले लंबे समय तक उसका स्थान सुरक्षित है। श्रीदेवी और जयाप्रदा आज की सबसे व्यस्त हीरोइनें हैं। इस कतार में अब डिंपल का नाम भी जुड़ गया है।

लेकिन जहां डिंपल आज पहुंची है इसमें क्या सिर्फ भाग्य का योगदान है या स्वयं डिंपल की भी कोशिशें हैं? निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट ने जब 'काश' की हीरोइन ढूंढ़नी शुरू की, तो शबाना आजमी और स्मिता पाटील जैसी अभिनेत्रियों के बजाय डिंपल पर ही उनका ध्यान क्यों केंद्रित हुआ?

"महज इसलिए," महेश भट्ट बताते हैं, "क्योंकि जिस तरह की भूमिका मेरी फिल्म में थी, उसका अनुभव डिंपल को अपने पारिवारिक जीवन में बखूबी हो चुका था। लेकिन अनुभव का इजहार करने की उसकी क्षमता पर मुझे थोड़ा संदेह भी था। इसका कारण यही था कि डिंपल की 'इमेज' एक नाचती-गाती सुंदर लगने वाली 'ग्लैमर गर्ल' जैसी थी। मैंने जान-बूझकर ऐसी स्थितियों में उसे 'जैसा वह चाहे वैसा करे' छोड़ दिया। बस इतना मंत्र जरूर उसके कान में फूंक दिया, किसी भी सीन की शूटिंग करते वक्त यह बिलकुल न सोचे, उसकी सुंदरता बिगड़ रही है। लिहाजा उसने जिस तरीके कुछ दृश्यों में अपनी भावनाओं का विस्फोट किया, वह उसकी 'ओरिजनल एक्टिंग' के बेहतरीन नमूने के रूप में हमेशा याद किया जायेगा... 'काश' देखने के बाद कई फिल्म समीक्षकों ने हीरोइन के रूप में डिंपल का चुनाव करने के लिए मेरी प्रशंसा भी की।"

रमेश सिप्पी का कहना है, "डिंपल में एक नहीं अनेक खूबियां हैं। सुंदरता है, चंचलता है और एक ऐसी उदासी है जो दर्शकों को झकझोर देती है।

सिप्पी के कथन में अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें जो सचाई है, वह जाहिर होती जा रही है। शुद्ध व्यावसायिक फिल्मों के लिए डिंपल बहुत जरूरी बनती जा रही है और उन निर्देशकों के लिए जो व्यावसायिकता से पहले कलात्मक रुचि को मान्यता देते हैं। वह स्मिता पाटील या शबाना आजमी जैसी संवेदनशील अभिनेत्रियों से उन्नीस नहीं। तीस साल की उम्र में उसने वह जगह बना ली, जिसकी वह सही मायनों में हकदार थी।

—हरीश तिवारी

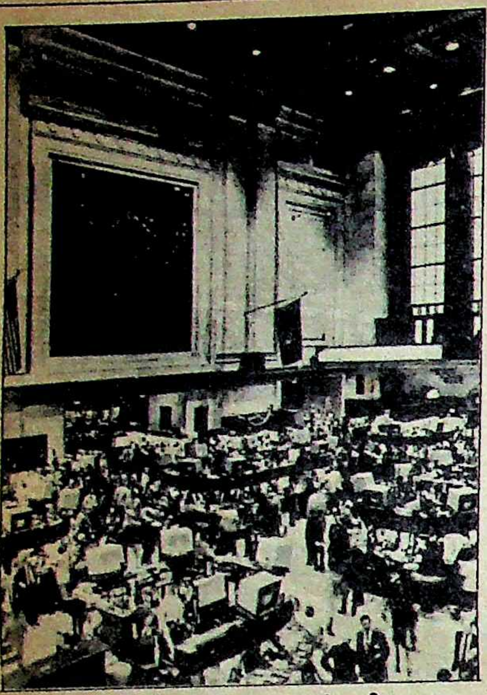
न्यूयार्क शहर के शेयर बाजार का अंदरूनी दृश्य

अमरीका दीवालिया होने के कगार पर

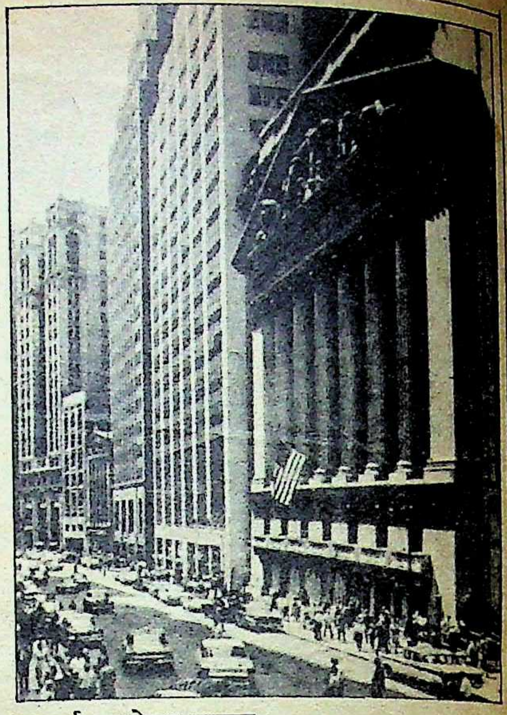
न्यूयार्क का शेयर बाजार

अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में विश्व शेयर बाजार में आयी अभूतपूर्व गिरावट ने विश्व के पूंजी निवेशकों को सिर्फ एक दिन में एक हजार बिलियन डालर अर्थात १५० खरब रुपयों की चोट पहुंचायी है। यह रकम हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पाद से सात गुना अधिक है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, अमरीका के पूंजी निवेशकों को। उन्हें ५०० बिलियन डालर अर्थात ७५ खरब रुपयों की क्षति पहुंची है, जिससे अमरीका की अर्थ-व्यवस्था के पूरी तरह चौपट हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया भर में कर्ज बांटनेवाला सबसे बड़ा साहूकार अमरीका आज विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क बन गया है। विश्व शेयर बाजार में यह अभूतपूर्व गिरावट क्यों आयी? इससे अमरीका ही सर्वाधिक प्रभावित क्यों हुआ? भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

अमरीका के विश्वविख्यात शेयर बाजार 'वाल स्ट्रीट' के लिए अप्रैल नहीं, बल्कि अक्तूबर का महीना कठोरतम साबित होता है। ५८ वर्ष पूर्व २४ अक्तूबर, १९२९ का 'वाल स्ट्रीट जरनल' का अंक कोहराम, घबराहट, आपाधापी और आम बेचैनी की कथाएं प्रकाशित कर रहा था, क्योंकि न्यूयार्क शेयर बाजार के शेयरों में भारी गिरावट आयी थी तथा उस दिन की समाप्ति पर बाजार का लगभग सफाया हो चुका था। इस बार १९ अक्तूबर के अशुभ सोमवार को यह घटना घटित हुई, जब डाऊ जोन्स सूचकांक में भारी गिरावट आयी और वह २२४७ से घटकर १७३९ रह गया। इस प्रकार उसमें ५०८ अंकों अर्थात २२ प्रतिशत की गिरावट आयी। यह १९२९ में आयी इतिहास की सबसे बड़ी मंदी की गिरावट की दर से दुगुनी है।

अमरीका के शेयर बाजार वाल स्ट्रीट की सड़क न्यूयार्क की अन्य सड़कों जैसी खुली और चौड़ी नहीं है। दरअसल, यह दिल्ली के करोलबाग के अजमलखां रोड की संकरी सड़क से अधिक चौड़ी नहीं है। इसके दोनों ओर की विशालकाय इमारतों के दड़बानुमा कमरों में शेयर दलालों, उनके क्लर्कों और उनके सर्वव्यापी टी०वी० सेटों का आवास है। चार माह पूर्व जब मैं न्यूयार्क में था, तो एक दिन के लिए मैं वाल स्ट्रीट, या शेयर दलालों की बोली में 'वाल' भी गया। वहां मैंने सड़क के किनारे के एक छोटे स्टाल से एक हाट़ डाग खरीदा, जिसमें सरसों का भरपूर मिश्रण था। उस हाट डाग का मूल्य दो डालर था जो न्यूयार्क के किसी इलाके से दुगना महंगा था। पर वाल स्ट्रीट में धन की कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां का लगभग हरेक व्यक्ति करोड़पति है। यहां तक कि क्लर्क लोग १२५००० डालर सालाना या लगभग १५०००० रु० मासिक कमाते हैं। वे हाट डाग ही खाते हैं, क्योंकि किसी रेस्ट्रा में ढंग का खाना खाने का समय उनके पास नहीं है। फिर किसी ऐसे आपाधापी के बाजार में, जहां एक मिनट में आप लाखों कमा या गंवा सकते हैं—भोजन में एक घंटा लगाना बहुत महंगा पड़ता है।

पूर्व संकेत : यह गिरावट आशा से कुछ पहले, कदाचित एक वर्ष या इससे पूर्व आयी है, किंतु इसकी पूर्ण संभावना थी। इसके आगमन के पन्द्रह दिनों पूर्व 'टाइम' समाचार पत्रिका में 'गिरावट में कितनी देरी?' शीर्षक से तीन पृष्ठ की एक कथा छपी, जिसमें संकेत किया गया था कि यह वर्ष बीतने के पहले ही कुछ भयंकर घटित होने जा रहा है। गिरावट के एक सप्ताह पूर्व इसी पत्रिका में 'सर्वनाशी अक्तूबर' शीर्षक की दो पेज की कथा छपी, क्योंकि गिरावट दरअसल २ अक्तूबर से शुरू हुई, जबकि सूचकांक लगभग शीर्ष पर था। किंतु १४ दिनों के भीतर वह २०० अंक गिर गया। यह १९ अक्तूबर के अशुभ सोमवार के वास्तविक सर्वनाश के पहले की बात है।

जून में अमरीका के दक्षिणी भाग के एक विश्वविद्यालय में पढ़ानेवाले एक साधारण भारतीय अर्थशास्त्री रवि बत्रा की 'द ग्रेट डिप्रेशन आफ १९९०' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने लगभग ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। बत्रा की ३०० रुपए मूल्य की यह पुस्तक न्यूयार्क टाइम्स की सर्वाधिक बिक्रीवाली पुस्तकों की सूची में १२ सप्ताह तक स्थान पाती रही तथा उसकी तीन लाख से अधिक प्रतियां बिकीं और बत्रा करोड़पति बन गये जो ऐसे अर्थशास्त्री के लिए अजूबा है जो बाजार के खेल में शामिल नहीं है। वह अब अमरीका

की एक जानी-मानी हस्ती बन गये हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में, जिसमें आनंद मार्ग के प्राउटिस्ट पब्लिकेशन्स के व्यापक उद्धरण दिये गये हैं, लिखा है कि अमरीका में बहुत से ऐसे धनी लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की संपत्ति अपने मुट्ठी में कर रखी है और यह अर्थ व्यवस्था तबाही की ओर ले जा रहा है। एक प्रतिशत अमरीकी परिवार का आज ३४ प्रतिशत संपत्ति पर कब्जा है, १९२९ में यह अनुपात ३६ प्रतिशत था जो आज की स्थिति के काफी करीब है।

गिरावट क्यों आयी ?: कौन है, इस भारी गिरावट या मंदी का जिम्मेदार, जिसने अमरीकी पूंजी निवेशकों का ५०० बिलियन डालर अथवा हमारी समूची राष्ट्रीय आय के लगभग तिगुने का ७५०००० करोड़ रुपए एक दिन में सफाया कर दिया? अन्य शेयर बाजारों और खासकर लंदन, टोकियो व फ्रैंकफुर्ट में भी ऐसी ही गाज गिरी, जिससे एक हजार बिलियन डालरों अथवा १५००,००० करोड़ रुपए की कुल हानि हुई जो हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पाद से सात गुना अधिक है। मूलतः यह रीगन प्रशासन और स्वयं राष्ट्रपति रीगन की गलती है, जिन्होंने अर्थ व्यवस्था में खतरनाक असंतुलन पैदा कर दिये हैं। रीगन ने सुरक्षा बजट में अनापशनाप वृद्धि की और करों में वृद्धि की बजाय उसमें कमी की। इसका नतीजा यह निकला कि गत छह वर्षों से अमरीकी बजट में घाटा निरंतर बढ़ रहा है। रीगन सरकार बाजार में अंधाधुंध उधार ले रही थी, क्योंकि वह हमारी सरकार की तरह मनमाने नोट नहीं छाप सकती। अमरीका का फेडरल रिजर्व बैंक जो एक स्वतंत्र संस्थान है, इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसी स्थिति में जबकि अमरीकी अधिक बचत नहीं करते और सरकार को वे अधिक उधार नहीं दे सकते, अधिकांश उधार जापान और जर्मनी से आया, क्योंकि इन देशों के पास डालरों का इतना बड़ा अंबार है कि उनकी समझ में नहीं आता कि उसका वे क्या करें? इन दोनों देशों का अमरीका से लाभप्रद व्यापार संतुलन है, जिसका अर्थ है कि इनके पास नकद डालरों के ऊंचे पहाड़ हैं। इसे इन्होंने अमरीकी सरकार को अमरीकी बांडों और सिक्योरिटियों में लगाकर उधार दिया है। ये भारी मात्रा में अमरीकी शेयर बाजारों में भी सट्टेबाजी करते हैं, क्योंकि प्रायः किसी विकासोन्मुख बाजार में वैध व्यापारिक गतिविधियों की तुलना में सट्टेबाजी से अधिक मुनाफा संभव है। अमरीका का बजट घाटा गत वर्ष २२० बिलियन डालर था जो अमरीका की राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत है। व्यापार घाटा भी लगभग इतना ही है। इस प्रकार अमरीका के कर्ज में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो इसके कुल राष्ट्रीय उत्पाद का दुगना है। यह उसी प्रकार है, मानो भारत १४००० करोड़ रुपए के घाटे बजट से गुजर रहा हो और उसका व्यापार घाटा भी इतना ही राशि का हो और ४,००,०० करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हो। यदि सचमुच हमारी यह स्थिति हुई होती, तो हम कब के तबाह हो चुके होते।

पहली गोली जापान की: कोई नहीं जानता कि यह फौरी अफरा-तफरी कैसे फैली? बस यही पता चला है कि पहली गोली जापानियों ने दागी। भारी घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण अमरीकी डालर का मूल्य गत कुछ वर्षों से लगातार गिरता जा रहा था और पिछले तीन वर्षों में उसमें ३० प्रतिशत की गिरावट आयी थी। जापानियों और जर्मनी के पास चूंकि खरबों (बिलियन्स) डालर थे, इसलिए वे कुछ समय के लिए अपने डालरों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। पहले उन्होंने उसे सोने में बदला, जिससे सोने के मूल्यों में वृद्धि हुई, फिर उन्होंने शेयर बाजार से अपने कोष को निकाल लिया। गिरावट के दो दिन पूर्व अमरीकी खजाना (ट्रेजरी) सचिव जेम्स बेकर ने यों ही कह दिया था कि उन्हें चिंता नहीं होगी, यदि डालर में और गिरावट आये। किंतु जितनी अधिक गिरावट होगी उतनी तेज मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि अमरीका बहुत बड़ा आयातकर्ता है और जब डालर गिरता है, तो मूल्य बढ़ जाते हैं। गत दो वर्षों में अधिकांश आयातित सामानों-कार से लेकर कैमरा-तक की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं और फारस की खाड़ी में हलचल के फलस्वरूप तेल के मूल्य में संभावित वृद्धि भी दरपेश थी। इन्हीं तत्वों के सम्मिलन से अंततः यह नौबत आयी। वैसे भी एक मुक्त-बाजार की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार हमेशा बलि का पहला बकरा बनता है। यह ऐसी अर्थव्यवस्था का एक थर्मामीटर है। जहां शेयर बाजार हर चीज तय करता है। सोवियत संघ में शेयर बाजार नहीं है। वहां बाजार-अर्थात आप और हम-नहीं, बल्कि मिखाइल गोर्बाचोव सब कुछ तय करते हैं।

> **अब जापान विश्व का सबसे बड़ा साहूकार राष्ट्र है जो अमरीकी अर्थव्यवस्था को एक मायने में खरीदता जा रहा है। टोकियो में जमीन की कीमत न्यूयार्क से दस गुना अधिक है और जापानी अमरीका में संपत्तियां वैसे ही खरीद रहे हैं, जैसे हमारे राजनेता सौदों से मिली अंधाधुंध रकम से स्विट्जरलैंड में फ्लैट्स खरीद रहे हैं।**

बहरहाल, यहां एक सवाल पैदा होता है। यदि जापानी और जर्मन अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, तो उनके शेयर बाजारों में भी गिरावट क्यों आयी? पहला, इनके बाजार बड़े घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर विपत्ति आती है, तो सब विपत्तिग्रस्त होते हैं। दूसरे, अधिकांश तथाकथित विकसित देशों की अर्थव्यवस्था एक-दूसरे पर, जितना हम सोचते हैं, उससे बहुत अधिक, निर्भर करती है। जापानी न केवल अमरीका को कार का निर्यात करते हैं, बल्कि उनकी कारों का निर्माण भी वहां करते हैं। ऐसा ही जर्मन भी करते हैं। दरअसल, फोर्ड जैसी जगविख्यात कारों के कल-पुर्जे एक दर्जन से अधिक देशों से आते हैं और यही बात अधिकांश औद्योगिक उत्पादों पर भी लागू होती है। अमरीकी कंपनियों ने अपने शेयरों को लंदन, फ्रैंकफुर्त और पेरिस के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कर रखा है, जैसे जापानी सोनी कंपनी न्यूयार्क में सूचीबद्ध है। कंपनियां इस पूरे क्षेत्र से धन उधार लेती हैं, क्योंकि अधिकांश करेंसियां विनिमेय (कनवर्टेबल) हैं और अधिकांश बैंक आपकी मनचाही करेंसी में खाता खोलती हैं। आप करोड़ों डालर न्यूयार्क या किसी अन्य स्थान के बैंक में ले जाकर उसे मनचाही करेंसी में बदल सकते हैं। दरअसल, ऐसी अनेक कंपनियां हैं जो मात्र विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री का काम करती हैं और किसी अन्य व्यापार की अपेक्षा अधिक कमाई करती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि वाल स्ट्रीट को जब छींक आती है, जैसाकि गत सोमवार से लगातार जारी है, तो हरेक को सर्दी-जुकाम हो जाता है। यह एक प्रकार का वित्तीय संक्रामक रोग है जो तमाम प्रमुख राजधानियों में फैलता है और अंततः सभी बीमार पड़ जाते हैं।

जापान साहूकार बना: अमरीका एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार (ऋणदाता) राष्ट्र था, किंतु अब विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार राष्ट्र बन गया है और यह सब एक दशक से कम समय में हुआ है। अब जापान विश्व का सबसे बड़ा साहूकार राष्ट्र है जो अमरीकी-अर्थव्यवस्था को एक मायने में खरीदता जा रहा है। टोकियो में जमीन की कीमत न्यूयार्क से दस गुना अधिक है और जापानी अमरीका में संपत्तियां वैसे ही खरीद रहे हैं, जैसे हमारे राजनेता सौदों से मिली अंधाधुंध रकम से स्विटजरलैंड में फ्लैट्स खरीद रहे हैं। कहा जाता है कि जापानियों ने न्यूयार्क के पांचवें हिस्से से अधिक भाग को खरीद लिया है तथा वे अब और तेजी से अमरीकी संपत्ति खरीद रहे हैं।

भारत पर असर: शेयर बाजार की मंदी भारत को इस रफ्तार से प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पश्चिम से अलग है। बंबई के दलाल स्ट्रीट में सोमवार १९ अक्तूबर का दिन न सिर्फ बहुत शांत था, बल्कि कुछ पावतियों (स्क्रिप्स) के मूल्य बढ़ गये। बहरहाल, कालांतर में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। विश्व शेयर बाजार में आयी भारी गिरावट एक मनोवैज्ञानिक आघात है जो अमरीकियों को भयभीत कर उनके खर्च की रफ्तार धीमी कर सकती है और इससे उस देश और अन्य देशों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि अमरीकी जरूरत से ज्यादा खर्च करने से इनकार कर दें, तो मांग में कमी हो जायेगी, और इस प्रकार अमरीका में हमारे निर्यात की मांग में कमी आ जायेगी, क्योंकि विकसित देश हमसे कम खरीदारी करेंगे। यदि अमरीकी अधिकारी समय पर नहीं चेते, तो इससे [illegible] ही दुष्चक्र शुरू हो जायेगा, जैसा ६० वर्ष पूर्व हुआ था।

—[illegible]

राजकीय उन्नयन बस्ती, कानपुर

इन्हें नरक से मुक्ति कब मिलेगी?

बेरोजगार: 'हबूड़ा' और 'भातू' युवक

अंग्रेजों ने जरायमपेशा घोषित कर 'हबूड़ा' और 'भातू' जनजातियों के १४० परिवारों के ७५० लोगों को पकड़कर सन् १९२२ में कानपुर के समीप एक खास खुली जेल में सशस्त्र सैनिकों की निगरानी में रखा था, ताकि वे लूटमार और डकैती का धंधा न कर सकें। जरायमपेशा जनजाति बस्ती (क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट) के रूप में विख्यात इस बस्ती के लोगों को आजादी के बाद आजाद नागरिक का दर्जा प्राप्त हुआ। इस बस्ती को राजकीय उन्नयन बस्ती का नाम दिया गया और पिछले चार दशकों में उनके उन्नयन के लिए सरकार ने लाखों रुपए व्यय किये, लेकिन क्या कारण है कि यह बस्ती अभी भी अपराधियों को जन्म देनेवाली बस्ती के रूप में कुख्यात है? महाराणा प्रताप के वंशज होने का दावा करनेवाले इस बस्ती के लोग आपराधिक धंधों में लिप्त रहने के लिए क्यों मजबूर हैं?

'नशे में धुत्त ताश खेलते पुरुष, अश्लील इशारे करतीं चंद युवतियां, कंधे पर बस्ता लटकाये, बीड़ी पीते बच्चों का झुण्ड और घर-घर में भट्ठी पर महुए की शराब बनाने में व्यस्त महिलाएं'— यह दृश्य किसी काल्पनिक उपन्यास का नहीं है, वरन यह यथार्थ है। रात का धुंधलका छाते ही कानपुर-बिठुर मार्ग पर स्थित 'राजकीय उन्नयन बस्ती' में रोजमर्रा का यह दृश्य देखा जा सकता है। कानपुर महानगर से १२ किलोमीटर दूर स्थित यह बस्ती सी०टी०एस० (क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट) के नाम से जानी जाती है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर के भारतीय तकनीकी संस्थान और कानपुर विश्वविद्यालय के ठीक बीच में बसी यह सी०टी०एस० बस्ती भी अन्तरराज्यीय शटरतोड़ गिरोह की जन्मस्थली है। बस्ती में 'हबूड़ा' और 'भातू' दो विमुक्त जनजातियों के लोग रहते हैं। 'हबूड़ा' और 'भातू' जाति के लोग चोरी, राहजनी, बटमारी, नकबजनी में सिद्धहस्त माने जाते हैं। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इन जातियों को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था।

राणा प्रताप के वंशज: 'हबूड़े' और 'भातू' स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। विश्वविख्यात भारतीय समाजविज्ञानी डा० डी०एन० मजूमदार द्वारा सन १९४१ में लिखित पुस्तक, 'रेस ऐंड कल्चर आफ इंडिया' के अनुसार, 'ये लोग महाराणा प्रताप की सेना में शामिल राजपूतों एवं अन्य सैनिकों के वंशज हैं। हल्दी-घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप की सेना मुगलों द्वारा मारी जाने लगी, तो उन्होंने अपने सैनिकों को मारे जाने व हथियार डालने की अपेक्षा जंगलों में भाग जाने की सलाह दी। ये राजपूत सैनिक जंगलों में जाकर विचरने लगे। जीवन-निर्वाह करने के लिए इन्होंने संगठित होकर छापामार शैली में लूटमार शुरू कर दी। कालांतर में यही इनका पेशा बन गया। भारत में अंग्रेजी शासन होने के बाद अंग्रेज सरकार ने आपराधिक कृत्य करने और उसे वैध माननेवाले लोगों के संगठित समूहों को आपराधिक जनजातियों के रूपों में माना। 'हबूड़े' और 'भातू' भी आपराधिक जनजातियों में शामिल कर दिये गये।'

'हबूड़ा' जाति के नाम का सन १९१४ के पूर्व कहीं भी उल्लेख नहीं है। सी०टी०एस० के ११९ वर्षीय निवासी किशन लाल (हबूड़ा) बताते हैं, "हबूड़ा नाम अंग्रेजों की देन है। वे हमें 'बुरा है-बुरा है' संबोधित करते थे। कालांतर में यही बुरा शब्द 'हबूड़ा' में परिवर्तित हो गया। कई अपराधी गोल (गिरोह) उस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, इटावा, मुरादाबाद आदि जिलों में लूटमार कर राजा और नवाबों की नींद हंराम किये हुए थे। नवाबों तथा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को काफी धन देकर मदद मांगी। अंग्रेजों ने अधिकांश 'हबूड़े' और 'भातू' गोल के सरदारों को बंदी बना लिया। सबको अलीगढ़ में नजीमुद्दौला के किले में बसाकर कपड़ा बुनने का व्यवसाय दिया गया। यहां से कुछ लोग फरार हो गये। बचे हुए लोग भी हरकतों से बाज नहीं आये। नजीमुद्दौला किले में बसे कुछ 'हबूड़े' और 'भातुओं' ने गोल बनाकर सन १९१४ में नवाब डण्डेबाज (अलीगढ़) के यहां चोरी की। बाद में पकड़ हो गयी। अंग्रेजों ने सबको तितर-बितर करने की नियत से कानपुर, मुरादाबाद, नजीमाबाद, मेरठ, गोरखपुर आदि स्थानों पर बसा दिया।"

पढ़ने की उम्र: ताश और नशे में मशगूल बस्ती के बच्चे

अपराधी से आजाद नागरिक: कानपुर सी०टी०एस० सन १९२२ में बनाया गया था। यहां 'हबूड़ा' और 'भातू' जाति के १४० परिवार (७५० व्यक्ति) रखे गये। सी०टी०एस० वास्तव में एक खुली जेल थी। इन्हें छोटे-छोटे मकान बनवाकर दिये गये! यह क्षेत्र ऊंची चहारदीवारी से घेर दिया गया। उन परिवारों को कहीं आने-जाने की छूट नहीं थी। अंग्रेजों ने इनके खाने-पहनने और सफायी की पूरी व्यवस्था की थी। सी०टी०एस० में उस समय एक पुलिस अधीक्षक और पुलिस बल रहता था। दो तरफ दरवाजे थे, जहां पहरा रहता था। सी०टी०एस० में ही एक सिलाई फैक्ट्री खोलकर उन लोगों को कपड़े सिलने में प्रशिक्षित किया गया। कुछ परिवार के लोगों को मजदूरी करने के लिए सिपाहियों की देखरेख में समीपवर्ती कल्याणपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा ले जाया जाता और शाम को इन्हें वापस सी०टी०एस० में बंद कर दिया जाता। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी खोला गया। १९४७ में देश आजाद होने के बाद भी सी०टी०एस० में रहनेवाले परिवार अपराधी जनजाति होने के आरोप में बंदी रहे। जब १९५२ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, तो पंडितजी और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने ३१ अगस्त, १९५२ को देश के सभी सी०टी०एस० निवासियों को 'विमुक्त जनजाति' के अन्तर्गत रखने की घोषणा की। उसी दिन इन्हें आजाद भारत के नागरिक की सभी सुविधाएं दी जाने लगीं। यही कारण है कि 'हबूड़े' और 'भातू' अपना स्वतंत्रता दिवस ३१ अगस्त को मनाते हैं। १९३५ में इस बस्ती का सारा इंतजाम समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया।

आबादी बढ़ी, हालात नहीं बदले

इस जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई छोटे-छोटे विद्रोह किये, पर विफल रहे। दस्यु सुलताना भी इसी जाति (भातू) का था। वह १९१७ में बिजनौर सी०टी०एस० से फरार हुआ था। सुलताना की १०७ वर्षीय बहन लौंगन अभी भी कानपुर सी०टी०एस० में रहती है। बूढ़ी लौंगन की आशाएं अभी भी जवान हैं, "बस्तीवाले सुधरेंगे जरूर, लेकिन इस बदलाव के लिए सरकारी प्रयास उतने सफल नहीं होंगे, जितने कि हमारे स्वयं के प्रयास।"

लौंगन का दुख है कि बस्ती के बच्चे जरा से बड़े हुए नही कि अपने पुरखों के आपराधिक किस्से बड़े चाव से सुनते हैं। फिर स्वयं हाथ में तमंचा या चाकू पकड़कर बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। बच्चों को बदले माहौल में रखना जरूरी है। साथ ही अंग्रेजी शासन में सिर्फ गुनहगार को ही सजा मिलती थी, जबकि वर्तमान में पुलिस निर्दोषों को प्रताड़ित कर गुनाह करने पर मजबूर करती है।

आजादी के बाद हरिजन: अब प्रश्न यह उठता है कि समाज कल्याण विभाग ने १९५३ से सी०टी०एस० के निवासियों के लिए क्या किया? इस बस्ती में क्या बदलाव आये हैं? सर्वप्रथम हरिजन समाज कल्याण विभाग ने इन लोगों को हरिजन घोषित कर आरक्षण की सुविधाएं देनी शुरू कीं। बस्ती के बाहर पुलिस गारद रहती थी, उसे १९६२ में पूर्णतः हटा दिया गया, ताकि ये लोग मानसिक रूप से स्वयं को अपराधी न समझें। किन्तु इस बस्ती के लोगों के रोजगार और बच्चों की पढ़ाई पर समाज कल्याण विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। १९२२ में बस्ती की आबादी ७५० थी, अब यह साढ़े चार हजार तक पहुंच गयी है। बस्ती में कुल ७५० मकान सरकार ने बनवाये हैं। एक मकान में परिवार के १५ से लेकर २४ सदस्य तक रहते हैं। ७५ प्रतिशत पुरुष नौकरियां करने लग गये हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आज भी १०० सिलाई मशीनोंवाली एक ही सिलाई फैक्ट्री है जो अधिकांशतः बंद रहती है। सिलाई फैक्ट्री में मात्र पुलिस-वर्दियां सिली जाती हैं। पहले पूरे प्रदेश की पुलिस-वर्दियां यहीं सिलती थीं। अब यह कार्य विभिन्न फर्मों को दिया जाता है। फैक्ट्री की क्षमता १२० लोगों को विभिन्न रोजगार देने की है। फैक्ट्री में कटर (कपड़े काटनेवाला) का काम करनेवाला श्रमिक अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के बाद १२ रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं कमा पाता। ५५ वर्षीय कटर रोशन के अनुसार, "मैं आजकल खीरे बेचकर २० रुपए कमा लेता हूं, कभी अधिक भी। फैक्ट्री तो हमारा खून चूसती है। पैंट या कमीज का पकड़ा कम दिया जाता है और जुर्माना हमारी मजदूरी में से काट लिया जाता है। ऐसे में कौन काम करेगा? मजदूरी इतनी कम है कि परिवार का पेट नहीं भर सकता।"

सी०टी०एस० के प्राइमरी स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि वह इमारत कभी भी गिर सकती है। स्कूल के अन्दर कमरों में शराब विरोधी पोस्टर लगे हैं। अधिकांश बच्चों का कहना है कि अध्यापक पढ़ाते ही नहीं। इस स्कूल में पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों को अन्य स्कूलों में दूसरी कक्षा में दाखिला मिलता है। संग्राम सिंह का १५ वर्षीय पुत्र श्रवण सिंह बताता है कि सी०टी०एस० के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहणं करके जब वह दूसरे स्कूल में गया, तो परीक्षा के बाद उसे दूसरी कक्षा में दाखिला दिंया गया। ऐसे स्कूल में दी जानेवाली शिक्षा उसके स्तर की पोल खोलती है। छात्रों को न तो छात्रवृत्ति ही दी जाती है और न ही सरकार द्वारा प्रदत्त मुफ्त पुस्तकें एवं शिक्षा-सामग्री की सुविधा। हां, बच्चों को गोल बनाकर स्कूल में सिगरेट पीते और ताश खेलते अवश्य देखा जा सकता है। अध्यापक अधिकांशतः स्कूल से गायब अथवा आपस में गप लड़ाते देखे जा सकते हैं।

आपराधिक वातावरण: बस्ती के निवासियों को सरकार ने प्रति परिवार ३ एकड़ जमीन भी दी थी। आबादी बढ़ने के कारण अब यह जमीन प्रति परिवार एक एकड़ बांट दी गयी। यहां न सिंचाई की सुविधा है और न ही खेती के लिए बीज व उपकरण उपलब्ध हैं। अतः यह जमीन बंजर पड़ी है। बस्ती

का माहौल दिनो-दिन बिगड़ता जा रहा है। दोपहर में भी नशे में डूबे मैदान के कोने में पसरे शराबी और ताश-सिगरेट में डूबी किशोरों की चौकड़ी का दिखायी दे जाना इस बस्ती के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। बस्ती के हर तीसरे घर में शराब बनना आम बात है। इसमें पुलिस भी उत्तनी ही दोषी है, जितने बस्ती के निवासी। साथ ही यहां की परिस्थितियां। कुछ लोगों का आर्थिक स्रोत मात्र सिलाई फैक्ट्री थी, वे मजबूरन शराब बनाकर पेट पालते हैं, लेकिन कुछ परिवारों के मुखिया नौकरीपेशा होने के बाद भी अधिक पैसा कमाने के लालच में शराब बनाते हैं। साथ ही सी०टी०एस० के लगभग हर घर में प्रतिदिन औसत सात बोतल शराब की खपत भी इनके शराब बनाने का मूल कारण बताया जाता है। कुल मिलाकर सी०टी०एस० बस्ती सरकारी अव्यवस्था के चलते अपराधियों का उत्पादन केंद्र बनती जा रही है। शराब के भभके फेंकता 'हबूड़ा' रंजीत सिंह बताता है, "मैं जिस कम्पनी में काम करता हूं, वहां महीने भर खपने के बाद जितना मुझे मिलता है, मैं शराब के धंधे में पुलिस का हिस्सा देने के बाद भी हफ्ते भर में उतना कमा लेता हूं। यह तो हमारा दोष है कि हमारी जाति अपराधी रही है। इसलिए हम पैदायशी अपराधी हैं। रोज हम अपने घरों में अपराध की तरकीबें सुनते हैं। चोरी करनेवाला आज भी हमारे यहां मशहूर होता है। अपराधी की लड़की किसी अपराधी को ब्याह दी जाती है। लड़के तो बचपन से ही सब कुछ सीखने लगते हैं। हमारे तो खून में ही अपराध है। यह हमारे पुरखों की धरोहर है। समाज आज भी हमें उसी निगाह से देखता है, तो हम अपराधी क्यों नहीं बनेंगे?"

रामरती कहती है, "भूखे पेट मरने से अच्छा मैंने शराब बनाने का धंधा करना समझा। तब भी मजबूरी थी, आज भी मजबूरी है। शहर में जाति जानते ही कोई नौकरी नहीं देता। देता भी है, तो एक भी सूई खोयी, तो चोरी का अपराध मुझ परं ही लगेगा, क्योंकि हमारी जाति ही बदनाम है। शराब तो बिक भी जाती है और इस धंधे में कम मेहनत और अधिक पैसा है। इसीलिए शराब बनाकर बेचती हूं।"

सर्वाधिक कमाईवाला थाना: सी०टी०एस० बस्ती कल्याणपुर थाने की इंदिरा नगर पुलिस चौकी के अन्तर्गत आती है। इस बस्ती के कारण यह सर्वाधिक कमाईवाला थाना समझा जाता है। बस्ती के अधिकांश लोगों की शिकायत है कि पुलिस नहीं चाहती कि शराब बनाने का धंधा बंद हो। जिन घरों में शराब बनती है, वहां से प्रतिमाह ३०० रुपए पुलिस को दिये जाते हैं। यदि लोग यह काम छोड़ना चाहें, तो पुलिस की आमदनी घटती है। बस पुलिस, छापों, प्रताड़ना और झूठे मामलों में फंसाने का सिलसिला शुरू कर देती है। मजबूरन वह परिवार पुनः शराब बनाकर पुलिस का हिस्सा शुरू कर देता है। शराब में नशा अधिक करने के उद्देश्य से बेशर्म झाड़ की पत्तियां तथा नौसादर का मिश्रण अथवा बैटरी डाल दी जाती है। श्याम सिंह में राष्ट्रीय स्तर के हाकी खिलाड़ी की सभी प्रतिभाएं थीं, किन्तु इसी शराब ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मशीनमैन खड़क

साक्षात्कार/ फूलचंद, प्रबंधक राजकीय उन्नयन बस्ती, कानपुर

'लोग ही नहीं चाहते कि यहां के हालात सुधरें'

'राजकीय उन्नयन बस्ती' के प्रबंधक फूलचंद को कानपुर के परगनाधिकारी डा० ललित वर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट में बस्ती के विकास के प्रति उदासीन माना है। प्रबंधक फूलचंद से 'माया' ने उक्त बस्ती की व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बातें की हैं। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश:

माया: इस बस्ती के निवासियों को सामान्य नागरिक के स्तर तक पहुंचाने के लिए एक प्रबंधक होने के नाते आप किस प्रबंध की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस करते हैं?

फूलचंद: सामाजिक स्थिति में परिवर्तन और हीन मानसिकता के निवारण का प्रबंध सर्वाधिक जरूरी है। आर्थिक रूप से अब ये इतने पिछड़े नहीं रहे। बस्ती के २५ प्रतिशत लोग सरकारी अथवा गैरसरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी करते हैं, इतने हीं लगभग मजदूरी, ठेला या छोटे-मोटे अन्य काम। गोपी चंद्र (हबूड़ा) तो समाज कल्याण विभाग में डिप्टी मैनेजर तक रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ये कमजोर भले हों, इनकी दशा शोचनीय नहीं है। अब इनके दूसरे आयामों के विकास पर बल देना होगा।

माया: जब लोग इतना कमाते हैं और शहर से जुड़े हैं, तो इस बस्ती से बाहर जाकर क्यों नहीं बसते?

फूलचंद: सामाजिक उपेक्षा, ज्यादा खर्च, अपनों व अपनी पारंपरिकता से लगाव, शराब बनाने की मनाही, ऐसे कुछ कारण हैं, जिनसे ये बस्ती से बाहर नहीं निकलते।

माया: क्या ये लोग शराब बनाते हैं?

फूलचंद: हां, पर बहुत कम।

माया: कितने घरों में बनती होगी, लगभग?

फूलचंद: यह कैसे बता सकता हूं। मेरे पास क्या लिस्ट रहती है? हां, ८०० परिवारों की इस बस्ती में पहले २०० से अधिक परिवार शराब बनाते थे, पर अब पुलिस की सक्रियता से ज्यादा-से ज्यादा ५० घरों में शराब बनती होगी।

माया: शराब और देह के खरीदार तो अधिकांशतः बस्ती के बाहर से ही आते होंगे। आप पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं करवाते?

फूलचंद: देह-व्यापार का धंधा बड़े गुप्त तरीके से होता है। धंधे में बस्ती के दलाल 'माध्यम' होते हैं। हमने कई मौकों पर बाहरी लोगों को रोका व उन्हें समझाया है। अब तो यह धंधा यहां लगभग बंद ही हो चुका है। रही शराब की बात, ये लोग साधारण भट्ठी पर महुये को सड़ाकर शराब बनाते हैं। कम नशीली उतरे, तो सैल (टार्च बैटरी) को पीसकर डाल देते हैं। बेशर्म जैसे जहरीले पौधे की पत्ती का रस शराब में डालना तो आम बात है। जब शराब बिकने से बच जाती है, तो ट्रक के कटे ट्यूबों में भरकर बेचते हैं, जो पीने वालों को सीधे-सीधे मौत की दावत देना है। बस्ती के ४-५ लोगों की आंखें इसी शराब से ही गयी हैं, कई मरे हैं। थोड़ा बहुत असर बाहरवालों पर पड़ा है, पर अभी भी यह धंधा रुक नहीं पाया है।

माया: शराब के धंधे का प्रचलन क्या इनकी बिगड़ी आर्थिक दशा का परिचायक नहीं?

फूलचंद: जी नहीं, ये यह धंधा अतिरिक्त लाभ के लिए करते हैं।

माया: इन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ हो, इसके लिए आपने कोई खास प्रबंध किया है या नहीं?

फूलचंद: मैंने आते ही कपड़ों का प्रबंध कर ३१ अगस्त को ही फैक्ट्री खुलवा दी, जो रोज खुलती है, लोगों को पूरा काम मिलता है, मेहनत करके अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं।

माया: पुरानी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त क्या कोई नयी योजना भी है, इनके सर्वांगीण विकास के लिए?

फूलचंद: १० लाख रुपए की लागत से एक ऐसी फैक्ट्री की योजना है जो इन्हीं बस्तीवालों द्वारा निर्मित सहकारी संस्था द्वारा चलायी जाये तथा वे ही शेयर-होल्डर भी होंगे। फैक्ट्री लगाने का आधा पैसा, कच्चा माल सरकार देगी और वही उत्पाद को भी खरीदेगी। फैक्ट्री के लिए ऐसा ही कार्य चुना जायेगा जो बस्तीवाले कर सकें। इस योजना से ५० हजार रुपए वार्षिक का फायदा बस्तीवालों को होगा। इनकी ऊसर पड़ी जमीन पर खेती हो सके, इसलिए मैंने १० बोरिंग करवायी हैं। ट्रैक्टर के लिए योजना सरकार को भेज दी है।

माया: इनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है?

सिंह ने भी शराब के धंधे में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण बस्ती में हैं।

देह व्यापार: कुछ वर्षों पूर्व यह बस्ती वेश्यावृत्ति के लिए शहरी लोगों की आरामगाह के रूप में भी काफी चर्चित हुई थी। कानपुर के कई रईसों के लिए यहीं से युवतियां भेजी जाती थीं। किन्तु अब यह पेशा लगभग नहीं के बराबर है।

फूलमती को बीस वर्ष की उम्र में पति ने छोड़ दिया था। उसने बताया, "तीन बच्चों के साथ जब कई दिन भूखी रही, तो मजबूरन देह बेचना पड़ा। अब तो यही पेशा है। मेहनत भी कम और दाम भी अच्छे।" हुस्ना व हसीना की भी यही कहानी है। तीनों अब बम्बई में जाकर देह व्यापार कर रही हैं। इसी प्रकार मंजू, प्रेमलता, कुसमी को भी उनकी मजबूरियां इस पेशे में खींच लायी हैं।

कलुआ जो शराब बनाने के साथ ही ग्राहकों को रात बिताने के लिए लड़कियां भी पहुंचा देने के लिए मशहूर है, ने बताया, "सरकार कहती है कि शराब मत बनाओ, पेशा मत करो। अरे पहले हमें रोजगार देकर भूखे मरने से तो बचाया जाये। जब सरकार हमारी नहीं सुनती, तो हम सरकार की क्यों सुनें?"

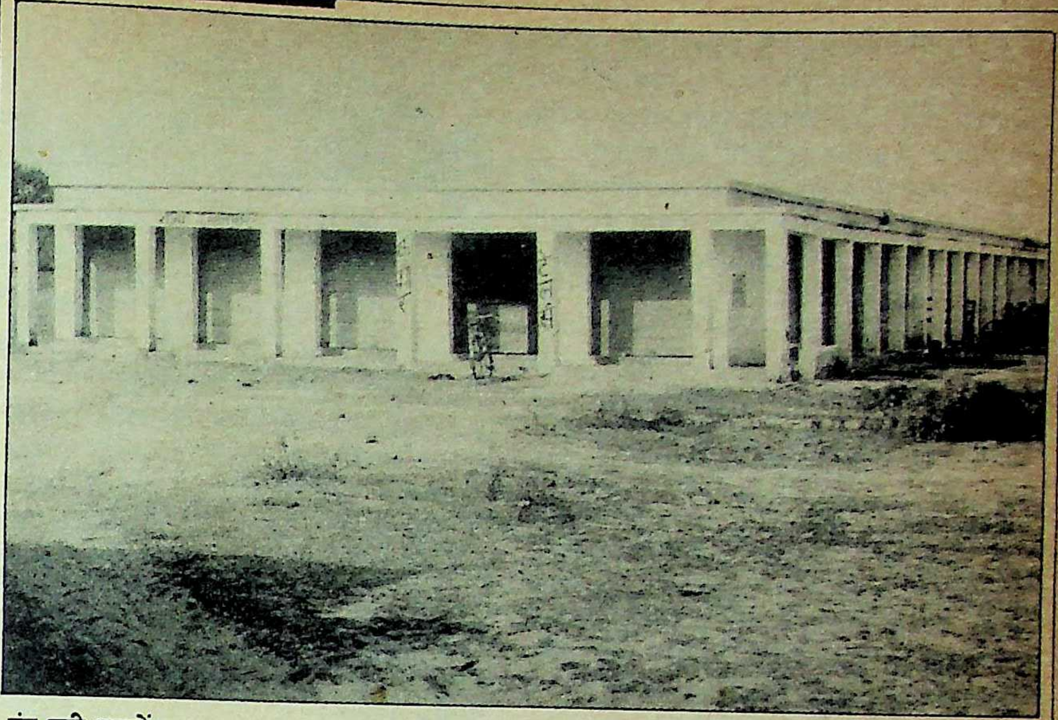

बंद पड़ी दुकानें

इसका अर्थ यह नहीं कि बस्ती में गरीबी का नंगा नाच है। कुछ परिवारों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी है। सभी आधुनिक सुख-सुविधाएं भी हैं। फिर भी उन परिवारों से जुड़े लोग स्वयं को शराब के पेशे से अलग नहीं कर पाये हैं। राधाकृष्ण उक्त बात स्वीकारते हुए बताते हैं, "अपराधी कौम का होने के कारण हम लोगों को तत्काल पुलिस अपराध में सान देती है। अशोक नगर चुंगी के समीप कोई हत्या हो गयी। पुलिस ने मेरे लड़के मोहन को उसमें फंसा दिया। उसका कुसूर मात्र इतना था कि जिस क्षेत्र में हत्या हुई, वहां वह बिजली का काम करने जाता था।"

इस बस्ती की ही देन अन्तरराष्ट्रीय चोर भगवती हबूड़ा है। गत वर्ष उसे मद्रास पुलिस ने चोरी के आरोप में बंदी बनाया, तो उसके पास २५ किलो सोना बरामद हुआ था। भगवती का लखनऊ में आलीशान मकान है फिर भी वह चोरी की आदत से मजबूर है।

सन १९८५ में बस्ती के लोगों के आर्थिक उत्थान व उन्हें रोजगार देने के लिए हरिजन समाज कल्याण विभाग ने बस्ती के किनारे २० दुकानें बनवायीं। इन दुकानों का आवंटन योग्यता व पात्रता के स्थान पर लाटरी डालकर किया गया। प्रत्येक दुकान-आवंटी को ५ हजार रुपए का ऋण भी दिया गया। रुपए के लालच में अधिकांश लोगों ने दुकानें लीं। हालात ये हैं कि १६ दुकानें आज तक खुली ही नहीं। अन्य दुकानें किराये पर उठा दी गयीं। जिन्हें दुकानें मिलीं, उनका कहना है, "जो लोग हमें (हबूड़ा-भातू) देखकर ही कन्नी काट जाते हैं, वह हमसे सामान क्या खरीदेंगे? सरकार ने इस उजाड़ में दुकानें बनाकर हमें फंसा दिया है। यहां बिजली भी नहीं है। बस हम प्रतिमाह ४१.६० रुपए दुकान की किस्त इसलिए अदा कर रहे हैं कि दुकान अपनी होते ही इसे ऊंची पगड़ी पर उठा दें।"

प्रबंधक के दावे: सी०टी०एस० बस्ती के प्रबंधक फूलचंद दावा करते हैं कि बस्ती में अपराधों में कमी आयी है। वेश्यावृत्ति तो लगभग समाप्त ही हो गयी है और शराब बननी भी बहुत कम हो गयी है। किन्तु कल्याणपुर थाने के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक सन १९८४ में सी०टी०एस० में १९५ अपराध पकड़े गये, जिनमें से १५८ मामले शराब बनाने व बेचने के थे। इसी प्रकार सन १९८५ में दर्ज २३० अपराधों में से १६७, सन १९८६ में दर्ज २३३ मामलों में से १९७ और १९८७ के प्रथम तीन माह में (३१ मार्च तक) पकड़े गये १३५ मामलों में से १०० अवैध शराब से सम्बन्धित रहे। उक्त आंकड़े ही बताते हैं कि सी०टी०एस० में शराब का धंधा कितनी तेजी से पनपा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां की शराब समीपवर्ती गांवों में काफी लोकप्रिय है।

प्रबंधक फूलचंद पर विमुक्त जाति परिषद, द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाये गये, जिसमें अधिकांश मकानों के आवंटन तथा सी०टी०एस० को मिलनेवाले धन में हेराफेरी कर अपने पैतृक स्थान बांदा में साबुन फैक्ट्री खोलने के आरोप मुख्य थे। इन मामलों की जांच कानपुर के परगनाधिकारी डा० ललित वर्मा ने की थी। डा० ललित वर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है, "बस्ती की १२७ एकड़ जमीन का लगान १० वर्षों से नहीं वसूला गया था। सीं०टी०एस० के वर्क इंसपेक्टर शर्मा ने लगान वसूली में अनियमितता की और रसीदें नहीं दीं। इसमें प्रबंधक फूलचंद के शामिल होने का आरोप है। इसकी जांच सतर्कता विभाग से करायी जांनी चाहिए।" परगनाधिकारी डा० वर्मा कुल-मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, "तथ्यों से स्पष्ट होता है कि

फूलचंद: हम आशा करते हैं कि यहां का प्राइमरी स्कूल अगले साल आठवीं तक का हो जायेगा।

माया: बस्तीवालों में सामाजिक, राजनीतिक जागरूकता पैदा करने का क्या कोई सार्थक प्रयास किया गया?

फूलचंद: मैंने बस्ती में बाकायदा चुनाव कराये और एक-एक क्षेत्र से तीन-तीन प्रतिनिधि चुने गये हैं। इनकी सम्मिलित कमेटी बस्तीवालों की परेशानियों, पुलिस अत्याचार और अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध कार्य कर रही है तथा गंदगी हटाओ, साक्षरता बढ़ाओ, इत्यादि सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अभियान भी छेड़ रखा है। अभी तो दो ही महीने हुए हैं, अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। सुधार के प्रयास तो पूरी निष्ठा से कर रहा हूं। देखिये कोशिश क्या रंग लाती है?

माया: आप पर आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि आपने बांदा स्थित अपने पैतृक निवास पर जो साबुन फैक्ट्री स्थापित की है, उसमें बस्ती के लिए आया धन लगाया गया है?

फूलचंद: यह आरोप आधारहीन है। मेरे या मेरे परिवार के पास खेती के अतिरिक्त कोई अन्य फैक्ट्री नहीं है। फिर जांच-अधिकारी ने सतर्कता विभाग से जांच कराने की संस्तुति की है। जांच में सब कुछ साफ हो जायेगा। दरअसल, बस्ती की भलाई के लिए मैंने जो कार्य किये, वही मेरे लिए अभिशाप बन गये हैं। यहां के कुछ लोग नहीं चाहते कि बस्ती के लोगों की हालत सुधरे।

भेंटवार्ता: संजय श्रीवास्तव

राजकीय उन्नयन बस्ती के प्रबंधक बस्ती के प्रति उदासीन हैं और बस्ती के प्रबंध व विकास में कोई भी रुचि नहीं लेते।" प्रबंधक फूलचन्द इन आरोपों को निराधार बताते हैं। (देखें साक्षात्कार)।

अंशुल नामक एक युवक ने 'अपराध व्यवस्था और क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट' विषय पर अपने शोध पत्र में लिखा है, "ऐसा भी नहीं है कि बस्ती के लोगों ने न सुधरने की कसम खा रखी है। सी०टी०एस० के कुछ नवयुवकों ने 'जाति विमुक्त सुधार परिषद संघ' बना कर अवैध शराब, वेश्यावृत्ति आदि का विरोध किया, तो पुलिस ने परिषद के कार्यकर्ताओं को शराब बनानेवाली महिलाओं के साथ झगड़े के आरोप में गिरफ्तार करने का क्रम जारी कर दिया। परिषद के सदस्यों ने कानपुर के जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया, तो पुलिस जुल्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। पुलिस ने इस संगठन को भंग कर दिया, क्योंकि इसमें शामिल युवक पुलिस द्वारा ले जानेवाली 'महीने' की रकम बन्द कराना चाहते थे।"

वास्तव में हबूड़े और भातू जाति के परिवार अब एक विशेष मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इनकी समस्याएं ही इन्हें पुनः अपराध की ओर मोड़ सकती हैं। अतः उनका निदान जरूरी है। यदि अंग्रेजी शासनकाल से अब तक बस्ती में हुए सुधार कार्यों का जायजा लिया जाये, तो ज्ञात होगा कि आजादी के बाद इनकी शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया।

शराब के धंधे में ज्यादा मुनाफा: हबूड़ा रंजीत सिंह

प्रसिद्ध समाज विज्ञानियों डा० माथुर, डा० डी०एन० मजूमदार ने इस जाति के लोगों को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, उनके अनुसार, "सी०टी०एस० में ३ वर्ष के बच्चों को बस्ती से दूर छात्रावास पद्धति के स्कूल में भेज देना चाहिए, ताकि बचपन से वे आपराधिक मानसिकता से परे रहें। साथ ही उन्हें विशेष तकनीकी प्रशिक्षण देकर अपने अभिभावकों के पास भेजा जाये, ताकि आनेवाली पीढ़ियों के साथ इनके माता-पिता भी सुधर जायें।"

लेकिन असली समस्या तो यह है कि आज तक प्रदेश सरकार ने कभी भी इन लोगों को अपराधी बनने से रोकने के लिए न तो समाज विज्ञानियों की मदद ली और न ही स्वयं कोई पहल की। यदि हालात यही रहे, तो वह दिन दूर नहीं कि जब कानपुर की यह बस्ती पूरे देश में सिद्धहस्त अपराधियों की आपूर्ति करनेवाली सबसे बड़ी मंडी बन जायेगी।

—कानपुर से, निशीथ जोशी और संजय श्रीवास्तव

सी० टी०एस० क्यों बना ?

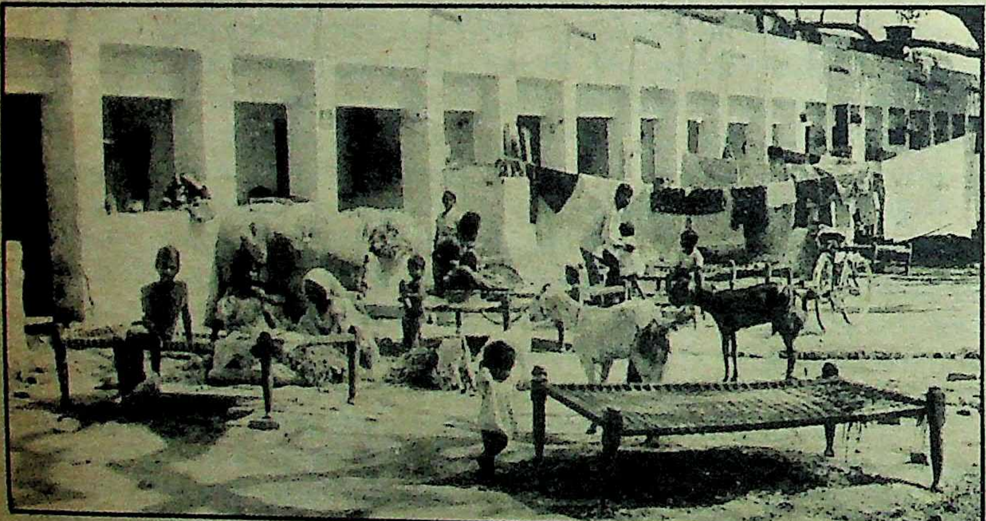

कानपुर में सी०टी०एस० (जरायम पेशा जनजाति बस्ती) क्यों और कैसे बनाया गया। इस संबंध में ११६ वर्षीय हबूड़ा किशनलाल एक दिलचस्प घटना सुनाते हैं।

सन् १९१४ में हबूड़ा परिवार अलीगढ़ में नजीमुद्दौला के किले में रहते थे। कुछ अन्य हबूड़े एवं भातू अलीगढ़ के आस-पास डेरा डाले हुए थे। उसी दौरान अलीगढ़ के नवाब डण्डेबाज की कुछ शोरेपुस्त ठाकुरों से ठन गयी। चूंकि नवाब डण्डेबाज को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, अतः ठाकुरों ने हबूड़ों की सहायता से नवाब को सबक सिखाने का फैसला किया। हबूड़ों से मदद मांगी गयी तो वह सहर्ष तैयार हो गये।

फिर एक रात नवाब डण्डेबाज के यहां चोरी हो गयी। नवाब के यहां से सारी नगदी और गहने तो चुराये ही गये, उसके गोदाम में चीनी के बोरों को भी हबूड़ों ने गायब कर दिया। इन बोरों को छिपाने का कोई रास्ता न देख उन्हें समीपवर्ती कुएं में शर्बत बनाने के लिए डाल दिया। इसके बाद हबूड़ों के सरदार के आदेश पर चोरी में शामिल सभी हबूड़ों ने नवाब डण्डेबाज की बेगम के उन खोखले आभूषणों जिनमें पानी रुक सकता था, के जरिये कुएं से शर्बत निकालकर पिया। अगले दिन जब चोरी का पता चला, तो बहुत कोहराम मचा, किन्तु चोरों का कोई सुराग पुलिस नहीं पा सकी।

उसी दौरान एक घटना और घटी। हबूड़ों ने चोरी में गांव के कुछ भंगियों और एक धोबी की सहायता ली थी। बंटवारे में एक धोबी के हिस्से में सौ-सौ के कुछ नोट आये थे। उस समय सौ का नोट सिर्फ रईसों के पास ही मिलता था। धोबी सौ का नोट लेकर एक वस्त्र व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने सौ का नोट देखा, तो उसे संदेह हुआ। उसने एक सिपाही को बुलाकर सारी बात बताई। धोबी पकड़ा गया। उसने चोरी में शामिल सभी लोगों के नाम उगल दिये। बस इसी घटना से अंग्रेज इतने खफा हुए कि उन्होंने हबूड़ों के सभी परिवारों को बंदी बनाकर कानपुर की ईदगाह के समीप लाकर बसा दिया। जब यहां भी ये हबूड़े अपनी हरकतों से बाज नहीं आये और कानपुर शहर में चोरियां बढ़ गयीं, तो उन्हें बिठूर रोड पर सी०टी०एस० बनाकर बसा दिया गया।

—निशीथ जोशी

उत्तर प्रदेश औद्योगीकरण की ओर

उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास की नयी अवस्थापना सुविधाओं ने देश के उद्यमियों में एक नया आकर्षण तथा उत्साह पैदा किया है। फलतः उद्यमी बड़ी संख्या में राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आ रहे हैं।

इसका स्पष्ट प्रमाण गत तीन वर्षों में राज्य को बड़ी संख्या में जारी किए गए आशय पत्रों, लाइसेंसों, डी०जी०टी०डी० पंजीकरणों की संख्या क्रमशः १५५ तथा ९२ और ३५४ थीं, जिन पर कुल पूंजी विनियोजन १३५० करोड़ रुपये था और २९,९८९ लोगों को रोजगार प्रस्तावित था। इनमें से २२५ करोड़ रुपये से विनियोजित ५० इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

वर्ष १९८६-८७ में राज्य को जारी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या डी जी टी डी पंजीकरणों को छोड़कर क्रमशः १७७ और ७५ थीं, जिन पर कुल रु० ४,२५१ करोड़ का विनियोजन होना था। इनमें से १६ इकाइयां रु० ३०७ करोड़ की लागत से स्थापित की जा चुकी हैं। वर्ष १९८६-८७ में ११० आशय पत्र, ६२ औद्योगिक लाइसेंस और २०२ डी जी टी डी पंजीकरण प्राप्त किये गए जिन पर रु० १२१२ करोड़ विनियोजन और १५,९३५ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थी। इनमें १६ परियोजनाएं १४८ करोड़ की लागत से कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में जो परंपरागत बाधाएं आती थीं उनमें प्रमुख थीं, ऊर्जा की कमी, विज्ञानकी ज्ञान का अभाव और तकनीकी रूप से कुशल कर्मियों की कमी। इन कमियों को दूर करने के लिए राज्य में बेहतर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी। सड़क औद्योगिक आस्थान अनुदान परक परिवहन सुविधा जैसी अवस्थापना संबंधी सहूलियतें दी गयीं और अन्य प्रदेशों से उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु अनेक कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में उद्योगबंधू की स्थापना की गयी है। इससे उद्यमियों को उस मुसीबत से नजात मिल गयी हैं जो उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था। उत्तर प्रदेश वित्त निगम के साथ लीड बैंक की पद्धति अपनाने से लोगों को स्वीकृति और वितरण के मामले लीड संस्था द्वारा संपन्न किये जाते हैं और विधिक औपचारिकताएं एक संस्था द्वारा पूरी की जाती हैं। पिकप द्वारा मर्चेंट बैंकिंग सेवा विकसित की गयी है। परियोजना कार्यान्वयन के आरम्भिक चरणों में व्यापारिक बैंकों से सम्बंध स्थापित करने में पिकप की इस्कट सेवा से उद्यमी अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना और उसके बाद बड़ी और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विनियोजन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।

निवेश में भारी वृद्धि

वर्ष १९६२ के २८७ करोड़ रुपये के मुकाबले १९८२ में २६२ करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था किंतु १९८४ से इस धनराशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और यह बढ़कर १९८४ में २२५३ करोड़ रु० और १९८५ में ३००० करोड़ रु० हो गयी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ७००० करोड़ रु० के विनियोजन से उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य है।

राज्य में स्थापित की जाने वाली मुख्य परियोजनाएं हैं, ३००० करोड़ रु० की लागत से गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्र, सलेमपुर, अलीगढ़ में रु० ८०० करोड़ रु० की लागत वाला एरोमेटिक संयंत्र, रु० १६८ करोड़ लागत की मनकापुर, गोंडा में स्थापित की जाने वाली स्विचगियर फैक्ट्री, रु० २०० करोड़ विनियोजन से काशीपुर में स्थापित की जाने वाली हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन की कागज परियोजना। इसके अतिरिक्त औरैया, इटावा में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से एक गैस क्रैर प्लांट स्थापित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

पिकअप द्वारा ४२४ बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के लिए मार्च १९८७ के अंत तक सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है और एक हजार करोड़ रु० से अधिक का विनियोजन सृजित किया गया है। निगम द्वारा इस समय संयुक्त क्षेत्र की ३५ परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन पर रु० २७५० करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है। पिकप द्वारा उभरते हुए उद्यमियों को १०२ इकाइयों के लिए सहायता दी जा रही है जिनमें से ४६ इकाइयों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। इन सामूहिक प्रयासों का यह परिणाम हुआ कि लगभग एक लाख लोगों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सका।

संतुलन पर ध्यान

उद्योगों के विकास में क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने के लिए पिकप और अन्य एजेंसियों ने धीरे-धीरे अपनी गतिविधियां पिछड़े क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दी हैं। इस समय ५७ जनपदों में से ५३ में पिकप की सहायता से नयी परियोजनाएं प्रारम्भ हो रही हैं। पिछले वर्षों में विकसित क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली स्वीकृतियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। ये स्वीकृतियां जो १९८२-८३ में ४२.२५ प्रतिशत थीं बढ़कर १९८५-८६ में ७५.७८ प्रतिशत हो गयीं। पिछड़े क्षेत्रों को १९८६-८७ में रु० ५७.१६ करोड़ की सर्वाधिक स्वीकृति दी गयी। कृषि के बाद लघु उद्योग क्षेत्र में ही सर्वाधिक रोजगार मिलता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को ही रोजगार के अवसर दिये जाते हैं। इस क्षेत्र का विकास आधुनिक और परंपरागत तकनीक जिसे उपयुक्त तकनीक कहा जाता है पर आधारित है।

इस प्रकार बढ़ी हुई औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप राज्य की आय रोजगार और उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। यह राज्य के सामाजिक जीवन और आर्थिक ढांचे के आधुनिकीकरण का सूचक है।

—एस०एम० जाफर

प्रदेश में लघु एवं ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन

देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश को अधिक संख्या में ग्रामीण उद्योगों की आवश्यकता है ताकि औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ-साथ गांव में रहने वाली जनता को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जा सकें। अपने गठन के समय से ही वर्तमान सरकार, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने और ग्रामीण लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए कड़ा परिश्रम कर रही है। इस प्रक्रिया में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का सृजन और उद्योगों के विकास में सहायक वातावरण प्रथम आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के ४२ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में चयन कर इन्हें 'अ', 'ब' तथा 'स' श्रेणियों में रखा है। इन जिलों में उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय विनियोजन अनुदान योजना शुरू की गयी है। इस योजना से बड़ी संख्या में उद्यमियों को लाभ पहुंचा है।

ग्रामीण उद्योग प्रदेश की संपूर्ण योजना का एक अंग है। ग्रामीण युवकों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने तथा गांवों में कृषि निर्भरता को घटाने की दृष्टि से ग्रामीण उद्योगों का महत्व आज और भी बढ़ गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इन उद्योगों से लाभ पहुंच सकता है। इनसे ग्रामीण लोगों का नगर की ओर पलायन भी रोका जा सकेगा। ●

वर्ष १९८५-८६ के दौरान इन उद्योगों के माध्यम से २,८,९५७ लोगों को सीधे रोजगार प्रदान किया गया। इसी अवधि में १२,९६३ ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गयी जबकि वर्ष १९८४-८५ में सहायता पाने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या १०,३८४ थी।

उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने ग्रामीण उद्योगों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दिशा में बोर्ड ने फलदायक कदम उठाए हैं। वर्ष १९८५-८६ में १५.३३ करोड़ रु० ऋण के रूप में और १.२३ करोड़ अनुदान के रूप में वितरित किये गये तथा भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, बंबई द्वारा ब्याज अनुदान योजना के अधीन ४.४७ करोड़ रु० के ऋण उपलब्ध कराए गए। वर्ष १९८५ में १,३३३.९५ लाख रुपये का ऋण तथा १२६.६० लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया जिसमें १२,३२३.६० लाख रुपये का माल उत्पादित किया गया।

खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत से ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक, तकनीकी एवं विपणन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें से मुख्य हैं दाल शोधन, ताड़ का गुड़ बनाने की इकाई, अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती उद्योग, बढ़ईगीरी एवं लोहारी फाइबर उद्योग, रेसिन उत्पादन, कत्था उत्पादन, गोंद उत्पादन, बेंत उद्योग, पोली क्लाथ उत्पादन इत्यादि । खादी ग्रामोद्योग आयोग भी उद्यमियों को ऋण व अनुदान प्रदान करता है। यह सहायता मुख्य रूप से कार्यशालाओं, मशीनों, अंशदान पूंजी, कार्यकारी पूंजी और प्रबंधकीय आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाती है। खादी इकाइयों को पांच से दस वर्ष तक के लिए सावधि ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है जबकि अन्य इकाइयों को चार प्रतिशत के ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है। निजी तौर पर कार्य करने वाले उद्यमियों से चार हजार रुपये तक के ऋण पर 'स्टैम्प' शुल्क नहीं लिया जाता है। चार हजार रुपये से अधिक ऋण पर ४७.५० रुपये प्रति हजार की दर से 'स्टैम्प' शुल्क लिया जाता है। सोसाइटी एवं सामाजिक संस्थाएं 'स्टैम्प' शुल्क से मुक्त कर दी गयी हैं। निजी कारीगरों को दो हजार रुपये तक का ऋण व्यक्तिगत जमानत पर तथा दो हजार से चार हजार रुपये तक का ऋण दो जमानतों पर प्रदान किया जाता है। चार हजार रुपये से अधिक का ऋण दो जमानतों या व्यक्तिगत संपत्ति को रेहन रखकर प्रदान किया जाता है।

ग्रामीण उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सबसिडी भी अनुमन्य है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त इकाइयां बिक्रीकर और क्रय कर से मुक्त रखी गयी हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी उत्पादन तथा नए माडल की कताई मशीनें, पहाड़ों पर अब हाथ का बना कागज, कम्बल और कपड़े बनाने के लिए विभागीय इकाइयां भी स्थापित की हैं। इन इकाइयों के माध्यम से वर्ष १९८५-८६ में ९६.८१ लाख रुपये का उत्पादन किया गया जबकि इसके पहले कें वर्ष में ९१.७३ लाख रुपये की वस्तुएं उत्पादित की गयी थीं। राज्य पुलिस और राज्य के अस्पतालों में आपूर्ति के लिए ४० माइक्रोम की कम्बलें आपूर्ति के लिए रेट कान्ट्रेक्ट पर कार्य हाथ में लिया है। सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर औद्योगिक संस्थान में एक संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए पांच एकड़ भूमि भी अध्याप्ति की गयी है।

मधुमक्खी पालन एक लाभकारी धंधा है। इस धंधे को प्रोत्साहित करने के लिए मधुमक्खी पालन की १२६ सहकारी संस्थाएं गठित की गयी हैं तथा इस उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नयी रणनीति अपनायी गयी है।

बहुत सी ग्रामीण इकाइयां पारस्परिक उद्योगों पर आधारित हैं। अब इन इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं इनमें कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। ग्रामीण उद्योगों के लिए युवकों को प्रोत्साहित करने हेतु 'ट्राइसेम' के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के उत्थान का व्यापक प्रयास

अल्प संख्यकों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान उत्तर प्रदेश सरकार का एक मुख्य ध्येय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक योजनायें चलाई गयी हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ सके।

इनमें से ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को रोजगारपरक तथा प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष १९८७-८८ में ऐसे १०० विद्यार्थियों में कुल ५ लाख रुपये की छात्रवृत्तियां बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आशा है प्राविधिक ज्ञान अर्जित करके विद्यार्थी नया वातावरण तैयार करने तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे।

आई.टी.आई. और पालीटेक्निक

सरकारी तथा गैर सरकारी एजेन्सियां, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा बहुउद्देश्यीय संस्थान और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए पालीटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस समय २३ पालिटेक्निक तथा ५ राजकीय इण्टरमीडिएट स्कूल कार्यरत हैं। वर्ष १९८६-८७ में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के डिप्लोमा स्तर के २३ विद्यालयों में कुल २३६ विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद तथा लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ को सामुदायिक पालीटेक्निक के रूप में विकसित किया गया है, जहां विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों/आश्रितों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लखनऊ पालीटेक्निक तथा राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद में विभिन्न व्यवसायों में अब तक क्रमशः ६७ तथा ११४ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद में ट्रांजिस्टर, मोटर वाइंडिंग, हाउस वायरिंग तथा टर्नर के व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्त एवं विकास निगम

अल्पसंख्यक समुदाय की कृषि, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में सहायता के लिए वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गयी है। निगम उन्हें वित्तीय प्राविधिक तथा विपणन की सहायता प्रदान करता है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में निगम ने जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष योजना आरम्भ की है। अल्पसंख्यक समुदाय के जिम्मेदार लोगों तथा वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। वर्ष १९८६-८७ में २३ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस योजना के अधीन इस प्रकार के आयोजन संगठित किये गये।

क्रेडिट कैम्प योजना

क्रेडिट कैम्प योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों तथा उद्यमियों को बैंकों की सहायता से ही एक स्थान पर वित्तीय सहायता की स्वीकृति तथा वितरण की व्यवस्था की गयी है। गत वर्ष लखनऊ, आजमगढ़, मुरादाबाद तथा शाहजहांपुर में क्रेडिट कैम्प आयोजित किये गये। कुल १५१४ लाभार्थियों को ५२१ लाख रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया। वर्ष १९८७-८८ में इस प्रकार के १० कैम्प आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एकीकरण समितियां

सद्भाव तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर एकीकरण समितियां गठित की गयी हैं। राज्य स्तरीय एकीकरण समिति के मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष हैं। सरकार ने सौहार्द बनाए रखने का दायित्व विशेष रूप से नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड संगठनों को सौंपा है। शासन इस कार्यक्रम में युवाओं को भी सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारियों से इस उद्देश्य के लिए युवा संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने के लिए स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी का शहीद दिवस राष्ट्रीय एकता के संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया और श्रीमती गांधी के दिवंगत होने के दिवस से कौमी एकता सप्ताह का श्रीगणेश हुआ। लोगों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे धर्म, भाषा क्षेत्र के नाम पर या अन्य मुद्दों पर हिंसा का सहारा नहीं लेंगे और किसी भी समस्या के समाधान के लिए शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीके अपनायेंगे।

सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ाई

सरकार ने सांप्रदायिक वैमनस्य तथा हिंसा भड़काने वाले तत्वों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। राज्य सरकार ने १९८६ में २७ लाख रुपये की धनराशि राहत के रूप में उन परिवारों में वितरित की जिनके संबंधी दंगों में मार दिये गये थे या घायल हुए थे।

विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यकों के भर्ती के लिए विशेष प्रयास किये गये। अल्पसंख्यकों के अपेक्षित प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न चयन समितियों का विधिवत पुनर्गठन किया गया। सशस्त्र पुलिस की पांच नयी बटालियनें सृजित की गयीं ताकि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना विकसित हो और उनकी भावनाओं का आदर हो।

सेवायोजन कार्यालयों में अल्पसंख्यकों को रोजगार दिलाने के लिए पंजीकृत करने की कार्यवाही के भेदभाव हटाने के उद्देश्य से समुचित कदम उठाये गये। विभिन्न कार्यालयों में इन समुदाय के अभ्यर्थियों को यथोचित दिशा निर्देश भी दिये जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग २,४२० अभ्यर्थियों को १९८६ के अंतिम तिमाहों में रोजगार दिया गया।

प्रतियोगी परीक्षाएं और अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से आगरा, गोरखपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में तथा फैज-ए-आम कालेज शाहजहांपुर में समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह के प्रशिक्षण मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी तथा आजमगढ़ में भी आयोजित किये जायेंगे।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन अल्पसंख्यकों को समुचित लाभ दिलाने की व्यवस्था की गयी। इसके अनुश्रवण के लिए कई सर्वेक्षण कराये गये। जिला स्तरीय समितियों में उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। आई.आर.डी.पी. द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के २३७५८ सदस्य सहारनपुर में १४३७० मुरादाबाद में १९३४७ बरेली तथा ४०४३४ आजमगढ़ में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए।

राज्य में इस समय उर्दू माध्यम के २१४२ स्कूल संचालित हैं जहां ३.७५ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षकों के ५,००० पद सृजित हुए जिन पर नियुक्तियां हो चुकी हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इस समय राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग कार्यरत है। उर्दू भाषा के विकास और प्रसार के लिए इस समय उर्दू अकादमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार इस अकादमी को लगभग २७ लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दे रही है। मौलाना आजाद मेमोरियल सोसायटी को लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने उर्दू भाषा की विशेष पुस्तकों के मुद्रण के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान दिया है। अभी तक कमेटी ने ७५९ पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए उनके लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान की है।

सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार हो, उनमें आत्मविश्वास की भावना दृढ़तर हो, विकास की मूलधारा से उन्हें जोड़ा जा सके ताकि वे भी आगे आकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के गुरुतर कार्य में अपनी भूमिका भी निभा सकें।

उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

बहुधा ऐसा कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की भृंखला में हुए विकास कार्यक्रमों में यद्यपि जनसाधारण की आय बढ़ी फिर भी उससे वांछित स्तर तक ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर नहीं हुई। हुआ यह कि ग्रामीण जनसंख्या के इस थोड़े से उच्चवर्गीय भाग को ही विकास की गतिविधियों के फलस्वरूप हुई आर्थिक सम्पन्नता का लाभ मिला। इस कारण शासन ने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन की नीति में परिवर्तन किया। और शासन ने यह निर्णय किया कि बजाए इसके कि धीरे-धीरे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ निर्धनतम व्यक्तियों तक पहुंचे और सीधे-सीधे गरीब से गरीब वर्गों को इन कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाया जाये।

इस दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास योजना गांवों के गरीब तबकों में सुधार लाने का माध्यम बनी। इसके अन्तर्गत उन्हें उत्पादक परिसम्पत्तियां और अन्य सामान देकर उनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाई जाती है। इस कार्यक्रम के लिए धन तथा सुविधाओं की व्यवस्था सरकार तथा व्यावसायिक बैंकों द्वारा की जाती है। छोटे किसानों की परिसम्पत्ति का २५ प्रतिशत मध्यम श्रेणी के किसानों को ३३ प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को ५० प्रतिशत की सहायता मिलती है।

समुचित विकास कार्यक्रम एक अखिल भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत पहले प्रदेश के कुछ चुने विकास खण्डों में की गयी। २ अक्टूबर १९८० को यह कार्यक्रम राज्य के सभी ८९० विकास खण्डों में लागू कर दिया गया। सन १९७९-८० तक लाभार्थियों की संख्या ५.०३ लाख परिवार थी। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३९.३६ लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठाये गये। अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में ६०० लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाता है। पहले गरीबी और अपेक्षाकृत सम्पन्नता के बीच ३५०० रुपये वार्षिक आय की सीमा रेखा थी। ऐसा समझा जाता था कि यदि परिवार की आय इस सीमा रेखा से अधिक होने पर उस परिवार की रेखा पार कर ली है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ३९.६ लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक विकास खण्ड में ८ लाख रुपये का व्यय किया जाता था। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक विकास खण्ड में वार्षिक व्यय की धनराशि बढ़ाकर १२ लाख कर दी जाये।

छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में १७३८८ लाख रुपये का व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप लाभ को १३८ प्रतिशत उपलब्धि हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९८५-८६ में ५.८१ लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। वर्ष १९८६-८७ में ६.०२ लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए और वर्ष ८७-८८ के लिए ६ लाख अतिरिक्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम से अनेक ग्रामीण परिवारों को अपने उत्पादक परिसम्पंत्ति प्राप्त करने में सहायता मिली जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें और गरीबी के दायरे से बच सकें। और रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के बजाए अपनी उत्पादक इकाइयों को कायम रख सकें।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम की नयी नीति के अनुसार इसके कार्यान्वियन के लिए कुछ नये तत्व सम्मिलित किये गये हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लाभार्थियों में गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सके। वर्ष १९८७-८८ में ३ लाख ऐसे परिवारों का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी गयी है। ऐसे जिलों में जहां इनकी संख्या जनसंख्या की ३० से ५० प्रतिशत के बीच है वहां चुने हुए परिवारों में से ५० प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त ३० प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए विशेषकर वे जो गृहस्थी का भार चलाती हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जायेगी। सामूहिक रूप से उनकी उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नयी नीति की अन्य विशेषता यह है कि लाभार्थियों के चयन में गांव-सभा और जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर कार्यपालिका को जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिक उत्तरदायी बना दिया है। कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सहायता देने के लिए गांव और बालक स्तर पर परामर्शदात्री समितियां गठित की गयीं हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका की सराहना की गयी है और कार्यान्वियन स्तर पर और उनकी अधिकाधिक सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

गरीबी रेखा की नयी नीति के अन्तर्गत अर्जन की वार्षिक आय पुनर्भाषित कर दी गयी है। किसी परिवार की वार्षिक आय ६,४०० रुपये से कम होने पर उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, परन्तु सहायता के लिए योग्य परिवारें के चयन में उन परिवारों को वरीयता मिलेगी जिनकी वार्षिक आय ४,८०० रुपये से कम है। इसके अतिरिक्त, इस सम्पूर्ण कार्यक्रम का दूसरे वार्षिक आय ४,८०० रुपये से कम है। इसके अतिरिक्त, इस सम्पूर्ण कार्यक्रम का दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रमों से इस तरह तालमेल बैठाया गया है जिससे हथकरघा, रेशम उद्योग, सामाजिक वानिकी, पशुधन विकास तथा अन्य कृषि पर आधारित कार्यक्रमों से भी इन लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके।

—एस०एम० जाफ़र

विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान

जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य के विकास का कार्य एक चुनौती है। एक ओर हिमालय की ऊंची चोटियों और दूसरी ओर बुन्देल खण्ड का पठारी भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सम्पन्नता और पूर्वी अंचल का आर्थिक पिछड़ापन। इन सबमें संतुलन स्थापित करना निश्चय ही कठिन कार्य था। आजादी के बाद इस दिशा में भरसक प्रयत्न किये गये। इनका उत्साहवर्धक परिणाम भी देखने को मिला है। लेकिन ग्यारह करोड़ आबादी वाले प्रदेश में प्रत्येक को विकास का लाभ पहुंचा सकने का संकल्प अभी पूरा होना शेष है। अबाध गति से इसी दिशा में यात्रा का हर पड़ाव हर साल पार हो रहा है और अगले पड़ाव का लक्ष्य सामने रखते हुए यात्रा जारी है। संसाधनों का अभाव अथवा विपरीत परिस्थितियों से प्रदेश विचलित नहीं हुआ। लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा ने मनोबल बढ़ाया है और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन और समयबद्ध कार्यान्वयन करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है।

यह सत्य है कि सभी लोगों की सभी आवश्यकताएं एक ही समय में पूरी नहीं हो सकतीं। उसके लिए एक निश्चित और संतुलित व्यवस्था अपनानी पड़ती है तथा उपलब्ध संसाधनों की परिधि के भीतर योजनाओं का निरूपण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होता है।

खाद्यान्न के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने न केवल आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली अपितु अतिरिक्त भण्डार का लाभ देश के उन भागों में भी दे रहा है जो अन्न के मामले में अभावग्रस्त हैं। इस सफलता के पीछे किसानों का परिश्रम और खेती की नयी विधियों के लिए उनका लगाव तथा रसायनिक उर्वरकों का उपयोग है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन १२.९२ कुन्तल तथा गेहूं का १८.७६ कुन्तल तक पहुंच जाना इन प्रयासों की सार्थकता दर्शाता है। बीते हुए वर्ष में खाद्यान्न का कुल उत्पादन ३१६.६७ लाख मीटरिक टन हुआ। इस वर्ष (१९८७-८८) कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य ३४५.२० लाख टन रखा गया है। इसके अतिरिक्त १५ लाख टन तिलहन तथा ३१.५० लाख टन दलहन उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के २५ लाख गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग, खाण्डसारी और गुड़ उद्योग में लगे लोगों का हित साधन सरकार का प्रमुख दायित्व रहा है। इन दोनों का प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में प्रमुख स्थान है। इस पेराई सीजन में तीन कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन (८४६.४२) लाख टन सर्वाधिक चीनी उत्पादन (२४.४५) लाख टन सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार (५ मीटरी टन) गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को दिये गये गन्ने की कीमत का ८९ प्रतिशत भुगतान कर दिया गया।

निराश्रितों को मदद

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष १९८६-८७ में ३.५० लाख अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि कुल लाभार्थियों की संख्या ३.८० लाख तक पहुंच गयी। समाज कल्याण की दिशा में एक नया महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। नितान्त निराश्रितों को सहायता का प्रावधान करके ऐसे निराश्रितों का, जिनके पास जीवन-यापन का कोई स्रोत नहीं, प्रदेश भर में सर्वेक्षण कराया जायेगा।

किसानों की अच्छी किस्म का बीज उर्वरक तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। प्रचार माध्यमों से किसानों को जानकारी दी जाती ताकि इस जानकारी के आधार पर वे प्रदत्त सुविधाओं और रियायतों का सामयिक लाभ उठा सकें। किसानों की ही जमीन पर उन्नत बीच की नर्सरियां लगाने का क्रम जारी है। मिट्टी का परीक्षण भी किये जाने की पूरी व्यवस्था है ताकि मिट्टी को ठीक उर्वरक मिल सके और किसान को ठीक बीज। विश्व बैंक की सहायता से "ट्रेनिंग एण्ड विजिट" की योजना भी चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूरस्थ गांवों में उर्वरकों की सुलभता की दृष्टि से स्थान-स्थान पर वितरण केन्द्र खोले गये हैं। इसी प्रकार कीटनाशक दवाओं के छिड़काव आदि की भी व्यवस्था है।

फसल बीमा योजना का विस्तार बाजरा और सोयाबीन के लिए कर दिया गया है। शाकभाजी बीजों के मिनीकिटों पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को ५० प्रतिशत छूट प्राप्त है।

दो बार प्रथम

गरीबी दूर करने, उत्पादन बढ़ाने, पिछड़े लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध राज्य सरकार ने जिस उत्साह, लगन और निष्ठा से बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू किया उसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों से उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों की तुलना में लगातार दो बार प्रथम स्थान लेने का श्रेय मिला। लगभग सभी प्रमुख मदों में उत्तर प्रदेश को शत-प्रतिशत अथवा इससे अधिक उपलब्धि प्राप्त हुई। इन सफलताओं से प्रोत्साहित होकर वर्ष १९८७ में ७.६६ लाख परिवारों की एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में लाभान्वित करने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ९२३ लाख मानव दिवस सृजित करने, २०,००० लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने, ९७०० गांवों को पेयजल की आपूर्ति करने तथा ५०,००० परिवारों को आवास स्थल आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विकास की यात्रा अबाध गति से चलती रहे इसके लिए प्रदेश के भीतर शांति और व्यवस्था का होना अनिवार्य है। आपराधिक चुनौतियों, दंगों तथा साम्प्रदायिक तत्वों का सामना करने के लिए पुलिस बल को सक्षम बनाने के प्रयासों का क्रम जारी रखा गया। देश की सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य में अपराधों और अपराधियों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आयी। गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी गतिविधियों (निरोधक) के अधिनियम के अधीन १६१८ समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। निरन्तर जागरूकता के परिणामस्वरूप अपराधियों के ऊपर अंकुश रखा गया है।

प्रदेश की शिक्षा नीति में समय के अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश की गयी है। शिक्षा को यथा सम्भव व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए वाणिज्य वर्गीय पाठ्यक्रम प्रदेश के १०० इण्टर कालेजों में लागू किया जा चुका है। कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत तीस विद्यालयों में कंप्यूटर लगाये जा चुके हैं। नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत १० नवोदय विद्यालय पिछले वर्ष खोले गये थे। इस वर्ष नौ नवोदय विद्यालय और खोले जायेंगे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष १०.७३ लाख प्रौढ़ों को साक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अल्पसंख्यकों का उत्थान

अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए भी अनेक कारगर और व्यावहारिक कदम उठाये गये हैं और कोशिश की जा रही है कि योजनाओं का लाभ उन्हें शीघ्र मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार आये। इन वर्गों के निर्धन किन्तु मेधावी छात्रों के लिए व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पालीटेक्नीक अथवा आई०टी०आई० खोले गये हैं।

अल्पसंख्यकों को उनकी सुविधा के अनुसार खेती, व्यापार अथवा अन्य किसी व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी परामर्श देने और तैयार माल के विपणन करने में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, स्थापित है। ऋण शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। पिछले वर्ष लखनऊ, आजमगढ़, मुरादाबाद तथा शाहजहांपुर में आयोजित ऐसे ही शिविरों में १५७४ व्यक्तियों में ५२१ लाख रुपया ऋण के रूप में वितरित किया गया।

आगरा, गोरखपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों तथा फैज-ए-आम कालेज (शाहजहांपुर) में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में २१४२ उर्दू माध्यम के स्कूल चल रहे हैं। इनमें ३.७५ लाख छात्र शिक्षा पा रहे हैं। उर्दू अध्यापकों के लगभग ५००० पद स्वीकृत किये गये हैं। उर्दू भाषा तथा साहित्य की उन्नति और प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी कार्यरत हैं। राज्य सरकार इन संगठनों को यथा सम्भव आर्थिक सहायता दे रही है।

ये कुछ झलकियां हैं उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के उन सत्यप्रयासों की जो यहां के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने और आम लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इनसे इसकी स्वावलम्बी तथा समृद्ध राज्यों में गिनती होने लगेगी।

'शाही लिबास

एकमात्र सर्व विजेता!

प्योर वूल एवं पोलियस्टर वूल
सूटिंग्स, ट्वीडस, ब्लेज़र्स, निटिंग वूल
कम्बल, शालें व लोइयां

मैड्रिड, स्पेन में 'क्वालिटी टेक्सटाइल एण्ड
रेडी टू वीयर' वर्ष 1987 के लिए अंतर्राष्ट्रीय
स्वर्ण पदक के लिए चुना गया

Lal-imli
Dhariwal

111 वर्षों से

एक मनभावन संकलन

एक शहंशाह का 'सच'!

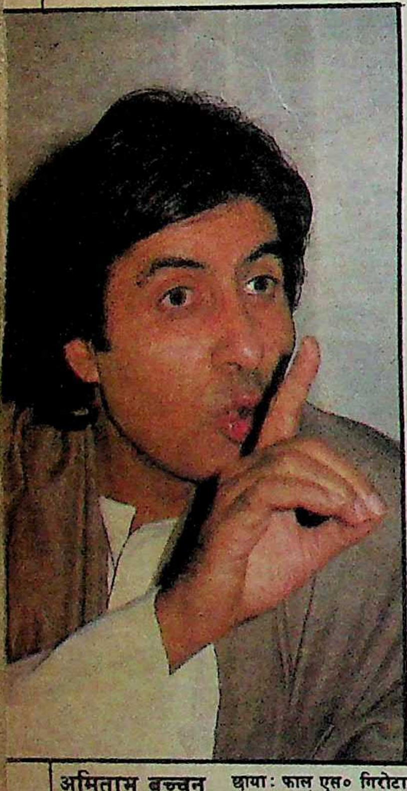

अमिताभ बच्चन छाया: फाल एस॰ गिरोटा

भले ही धाकड़ डायलागदां जावेद अख्तर ने दिल्ली दरबार को 'मीरजाफरों को नानी याद दिला दूंगा' डायलाग लिखकर न दिया हो, लेकिन मीरजाफरों की छुट्टी करा देने के लिए वह अमिताभ बच्चन के साथ एक पंचसितारा सूट में बड़े गोपनीय ढंग-से संवाद और पटकथा लिखने में जुट हुए हैं। 'जंजीर', 'दीवार', 'शोले' आदि फिल्मों में 'तालीबजाऊ संवादों' के जरिये अमिताभ को सुपर स्टार बना देने का ऐलान करनेवाले जावेद संवादों और सिचुएशनों के ऐसे-ऐसे तरकंश एकत्र कर रहे हैं कि हेमवतीनंदनों और वी॰पी॰ सिंहों की माइक पर बोलती बंद हो जाये। इन्ही 'दुश्मनों' के चक्रव्यूह के कारण अमिताभ को 'देवा' सहित कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, 'शहंशाह' का प्रदर्शन रोक देना पड़ा, उनकी फिल्मों को सिनेमा हाल में चला-चलाकर कुबेरपति बन बैठनेवाले वितरकों-प्रदर्शकों को इन्हीं फिल्मों के डिब्बे बिच्छू के डंक लगने लगे। हर फिल्म में खलनायकों की अंधाधुंध धुनाई करने के लिए बच्चों के 'बेताल' अमिताभ अपनी इस नयी फिल्म में इन खलनायकों की धुनाई करने के क्या तरीके ईजाद करेंगे, इसे तो दर्शक फिल्म के परदे पर देखेंगे, लेकिन बोफोर्स कांड में हुई बदनामी तथा फिल्म के साथ-साथ राजनीति के ब्रह्मांड में अपना सितारा धूमिल हो जाने के बावजूद उन्होंने जो खामोशी अख्तियार कर ली थी, उसे उनकी फिल्म 'सच' तोड़ेगी। 'सच' की कथा अमिताभ बच्चन के इलाहाबाद चुनाव से शुरू होगी और अंत बोफोर्स की सचाइयों एवं दुश्मनों की साजिशों पर अमिताभ की विजय के साथ खतम होगा। वी॰पी॰ सिंह से लेकर रामजेठमलानी तक के सभी आरोपों के जवाब वह 'सच' में देंगे, बहुतों को बेनकाब भी करेंगे। 'सच' के निर्माता-निर्देशक यों तो दिखावे के रूप में दूसरे 'नाम' देंगे, लेकिन असली कर्ताधर्ता अमिताभ ही होंगे। फिल्म 'इंकलाब' में उन्होंने भ्रष्ट नेताओं-मंत्रियों पर मशीनगन तान लिया था, और 'सच' में? थोड़ा इंतजार तो कीजिए सच की सचाई का।

करिश्मा जूही का

छोटी-सी उम्र में माडलिंग की दुनिया में हंगामा बरपा देने वाली जूही चावला अब अर्जुन हिंगोरानी की, १९८६ की सर्वाधिक महंगी बहुसितारीय फिल्म 'सल्तनत' में अभिनय करने के लिए रजामंद हो गयी थीं तो बकौल निर्माता-निर्देशक उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी भूमिका श्रीदेवी के समानांतर ही होगी। लेकिन बंबई की बरसात और फिल्म निर्माताओं के वायदे का भरोसा नहीं होता। निर्माता-निर्देशक की बात मानकर, 'सल्तनत' के प्रदर्शित न होने तक जूही ने दूसरी फिल्मों और सीरियलों के आफर ठुकरा दिये। लेकिन न तो भाग्य ने, 'सल्तनत' की बाक्स आफिस असफलता के कारण, उनका साथ दिया और न ही निर्माता-निर्देशक ने। और जूही, फिल्मी बगिया में खिलने के पूर्व ही मुरझा गयी।

"लेकिन मैं असफलताओं से न तो निराश होनेवाली हूं और न ही घबरा के भागने वाली।" कहने वाली जूही ने अपनी फिल्मी सफलता के लिए नयी मुहीम छेड़ दी है। कन्नड फिल्म 'प्रेमलोका' के लिए, निर्माता-निर्देशक की सलाह पर, जहां अपना नाम जूही से बदल कर जूली कर दिया, वहीं अब ग्लैमरस भूमिकाएं करने के लिए भी तैयार हो गयीं। उनके इस निर्णय का असर भी तुरंत दिखलाई पड़ा-नासिर हुसैन ने मंदाकिनी की जगह उन्हें 'कयामत से कयामत तक' में अपने बेटे के साथ ले लिया। एक निर्माता जितेन्द्र के साथ श्रीदेवी की जगह लेने के लिए बात कर रहा है, अब क्या करेंगी श्रीदेवी?

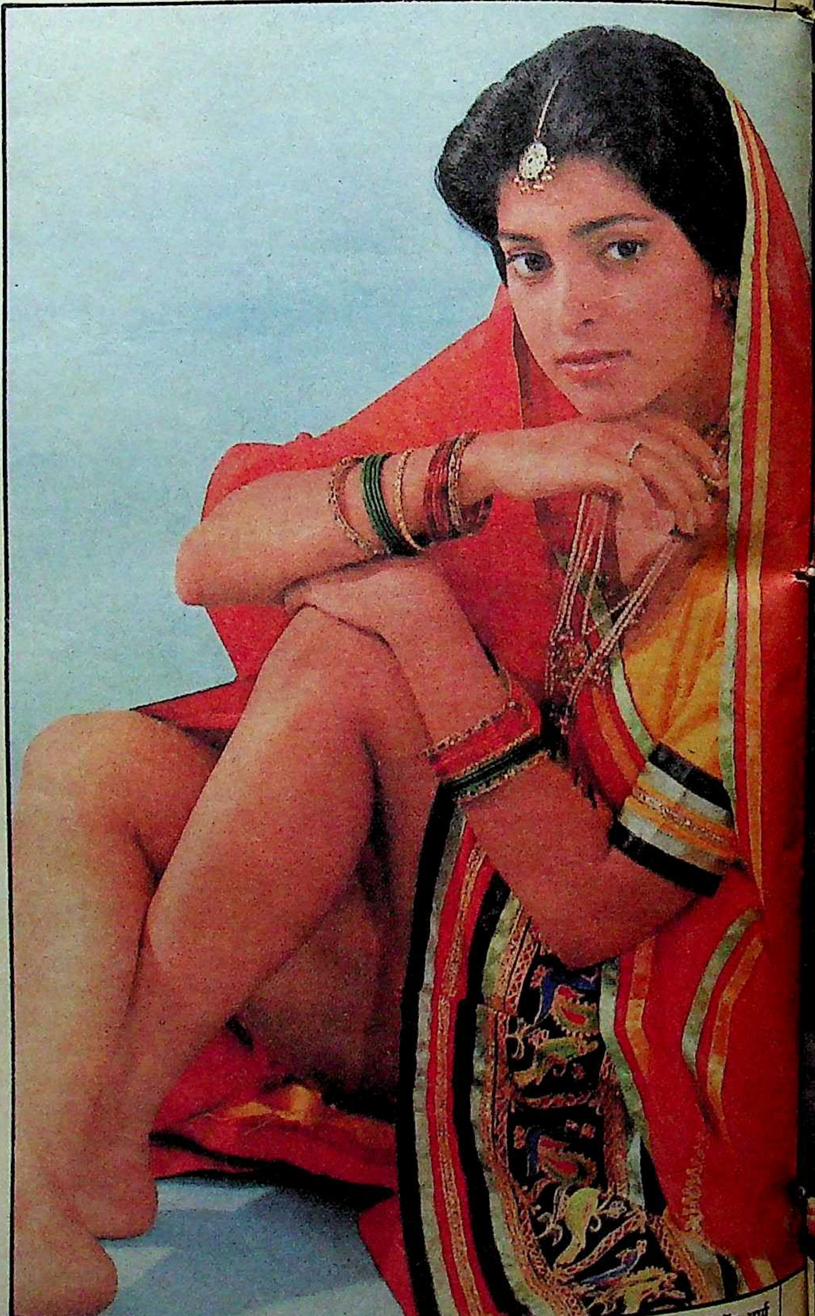

जूही चावला छाया: जितेंद्र आर्य

प्रेमा का आत्मबोध

अपने-अपने जमाने में सेक्स-बम और ग्लैमर गर्ल के नाम से विख्यात पद्मा खन्ना ('रामायण'), आशा सचदेव ('बुनियाद') तथा अरुणा ईरानी ('कालाजल') अपने ग्लैमर के चोले को उतार कर दूरदर्शन के छोटे परदे पर अवतरित क्या हुई कि उनका कायाकल्प ही हो गया।

''पारदर्शी या अत्यल्प कपड़ों में अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को बड़ी बेफिकरी से प्रदर्शित करनेवाली अभिनेत्रियों को सांगोपांग वस्त्र में भला दर्शक कैसे पसंद करेंगे''?— कहनेवाले फिल्मी पंडितों की व्याख्या को 'रामायण', 'बुनियाद' और 'काला जल' ने भले ही तोड़ दिया, लेकिन अपार लोकप्रियता दिलाकर भी न तो फिल्मों में उन्हें वापस ला सके और न ही दूसरे दूरदर्शन सीरियलों में उन्हें काम मिला।

पद्मा खन्ना, अरुणा ईरानी तथा आशा सचदेव के इस हस्र से एक और ग्लैमर-गर्ल प्रेमा नारायण जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गयीं और टी०वी० सीरियलों का आफर लेकर आनेवालों के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। उनका कहना है, ''टी०वी० सीरियलों में काम करने से लोकप्रियता मिलती है, लेकिन उस लोकप्रियता से क्या फायदा जो आपका कैरियर ही खतम कर दे। सती-साध्वी की भूमिका एक बार सीरियल में निभा लेने के बाद फिल्म-निर्माता उसे कम कपड़ोंवाली भूमिकाएं देने से हिचकिचाने लगते हैं कि एक बार परदे में उसकी खूबसूरती का जायजा लेने के बाद दर्शक की उसे बापरदा देखने की चाह खतम हो चुकी होती है।''

प्रेमा नारायण को लेकर फिल्म 'सती रूपकंवर' की योजना बना रहे फिल्म निर्माता को प्रेमा के इस आत्मबोध से बहुत गहरा धक्का पहुंचा।

प्रेमा नारायण

छाया: जितेंद्र आर्य

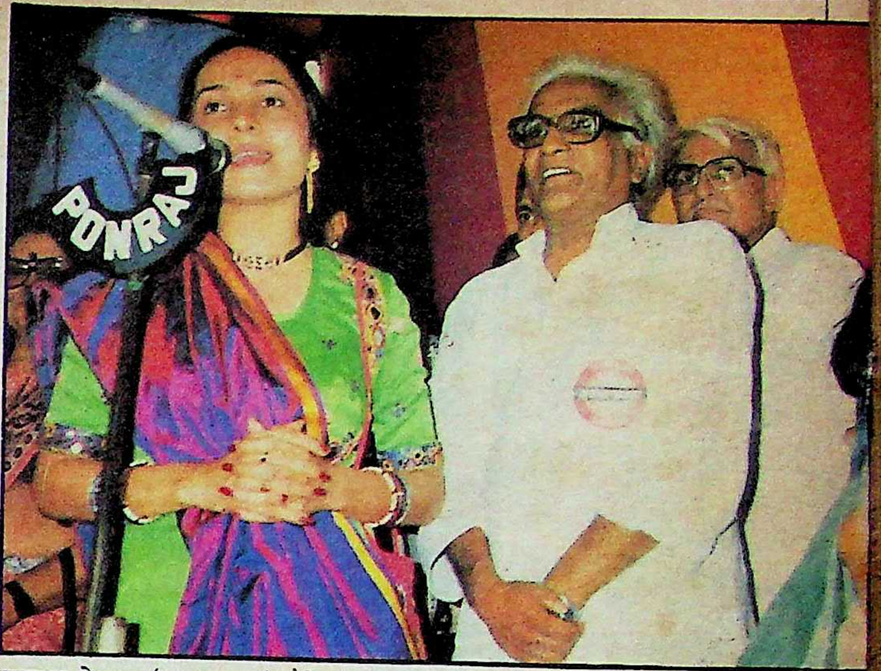

सुजाता मेहता (माइक पर) और 'सावधान' के मंत्री विनोद गुप्ता (दायें)

शबाना की नयी 'असिस्टेंट'!

अभिनेत्री से समाज सुधारक बन रही शब्बो अचानक इतनी अधिक व्यस्त हो गयी है कि चौबीस घंटे में हर फोन का जवाब एक ही मिलता है—'मेम साब बाहर गयी हैं।' जिस समय दिवराला सती कांड का हंगामा समूचे देश को आक्रांत किये हुए था, नये-नये नेताओं की बाढ़ आ रही थी, बंबई के लोगबाग शबाना को तलाश रहे थे। 'मेम साब बाहर गयी हैं' का जवाब सबने मान लिया कि शब्बो दिवराला के लिए कूच कर गयी है। लेकिन इस 'मुगालते' को तोड़ दिया, 'प्रतिघात' की ऐंग्री वुमन सुजाता मेहता ने यह बताकर कि 'शबानाजी अमरीका चली गयी हैं। उन्हें नासिक में स्त्री सुधार कार्यक्रम का उद्घाटन करना था, सो यह काम वह हमें थमा गयीं।'

बोलने में तीरदाज सुजाता ने नासिक की महिलाओं की सभा में जो भाषण दिया, उससे लोगों ने उनके नेता होने का ऐसा लोहा माना कि शबाना की सारी सभाओं में, उनकी गैरमौजूदगी में, अब सुजाता को ही बुलाया जाने लगा। और-तो-और, जब बंबई की समाजसेवी संस्था 'सावधान' ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धरावी (बंबई) में छह वेश्याओं का विवाह कर उनके सुधार का कार्यक्रम आयोजित, किया तो सदारत के लिए जिन तीन व्यक्तियों को चुना गया उनमें एक थीं—सुजाता मेहता। अन्य दो थे—नगर विकास मंत्री बी० सुब्रह्मण्यम तथा नगर प्रमुख धगन भुजबल।

बेचारी शब्बो जब बंबई वापस लौटी, तो पता चला उनके समाज सुधार का ताज तो सुजाता अपने सिर पर ओढ़े बैठी है। अब यह दूसरी बात है कि 'भरत' की तरह सुजाता ने शबाना का ताज उसे ही सौंप दिया।

ताज़गी का
एक पल...
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
...एक पल
में ताज़गी
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
रजनीगन्धा
पान मसाला
तुलसी ज़र्दा घराने की अनुपम भेंट
FUSION/RAJ/4

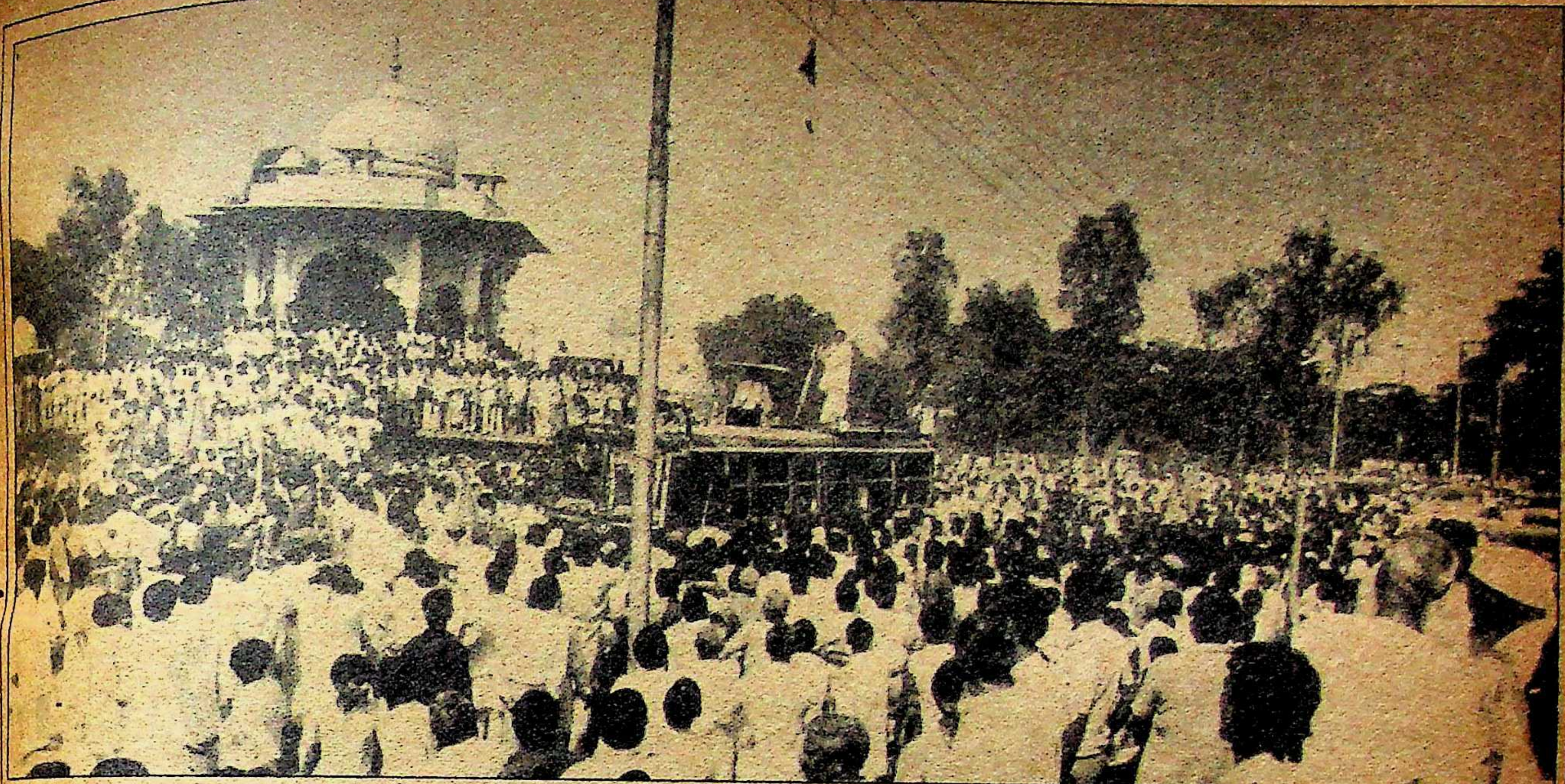

नोट भी चाहिए, वोट भी : बेगम हजरत महल पार्क में ११ लाख के 'क्रांति रथ' से भाषण देते मुलायम सिंह यादव

रैली का अर्थशास्त्र

मौजूदा राजनीतिक स्थिति से फायदा उठाने के चक्कर में विपक्षी पार्टियां रैलियों और रथयात्राओं में जुटी हुई हैं। इन आयोजनों में कांग्रेस-इ का जोरदार विरोध तो होता है, मगर सूखा संकट पर एक भी शब्द नहीं कहा जाता। इन रैलियों के साथ थैलियां बटोरने का काम भी जोरों पर है। अपनी पदयात्रा के दौरान अजीत सिंह (लोकदल-अ) को एक लाख रुपए की थैली मिली, वहीं मुलायम सिंह यादव (क्रांतिकारी मोर्चा) ने अपने ११ लाख के क्रांति रथ पर सवार होकर लगभग छह लाख रुपए बटोरे। सवाल यह उठता है कि जन संकट को भुलाकर जो दल 'नोट और वोट' बटोरने में लगे हैं, वे क्या कोई क्रांति ला सकते हैं? क्या वीर बहादुर या राजीव गांधी के भ्रष्ट प्रशासन को आखिरी धक्का देने में कामयाब हो सकते हैं? :

सूखा हो या बाढ़, उत्तर प्रदेश में सभी प्राकृतिक आपदाओं का उपयोग अब राजनीति के लिए ही होने लगा है। सूखा राहत के जो कार्यक्रम सरकार घोषित कर रही है वे आम जनता तक पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे मौके पर विपक्षी दल, जनता के सुख-दुख में हाथ बंटाने के बजाय उसकी मुसीबत की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां लाल करने में लग गये हैं। इसी का परिणाम है कि सूखे की विभीषिका से जूझते प्रदेश में रैलियों, पदयात्राओं और रथयात्राओं की बाढ़-सी आ गयी है। इन सभी का एकसूत्रीय कार्यक्रम है, 'राजीव हटाओ।'

विपक्ष द्वारा आयोजित उक्त रैलियां व प्रदर्शन वास्तव में आपसी प्रतिस्पर्धा और विखण्डता की सूचक हैं। वीर बहादुर सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा पाने में विफल विपक्ष अब केन्द्र से राजीव गांधी की सरकार को हटाने का सपना देख रहा है। प्रदेश में रैलियों और प्रदर्शनों की शुरुआत वास्तव में विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा की गयी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रमुख विपक्षी दल का रूप लेते देख अन्य दलों के नेताओं में खलबली मच गयी और उन्होंने रैलियों एवं सभाओं की योजनाएं बना डालीं।

विपक्षी दलों की ओर से इसकी पहल क्रांतिकारी मोर्चे के नेता मुलायम सिंह यादव ने की। हरियाणा में देवीलाल के 'विजय रथ' और आन्ध्र में एन०टी० रामाराव के 'चैतन्य रथ' की तर्ज पर मुलायम सिंह यादव ने सर्वप्रथम क्रान्तिकारी मोर्चे की ओर से १४ सितम्बर, १९८७ से 'क्रान्ति रथ' द्वारा प्रदेश भर की यात्रा करने की घोषणा की। प्रत्युत्तर में लोकदल-अ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने १० सितम्बर को ही मेरठ से लखनऊ तक की पदयात्रा शुरू कर दी। लोकदल-अ और क्रान्तिकारी मोर्चे की रैलियां वास्तव में सरकार के खिलाफ नहीं थीं। यह लोकदल-अ तथा लोकदल-ब द्वारा अपना जनसमर्थन दिखाने का एक बहाना मात्र था। इसी

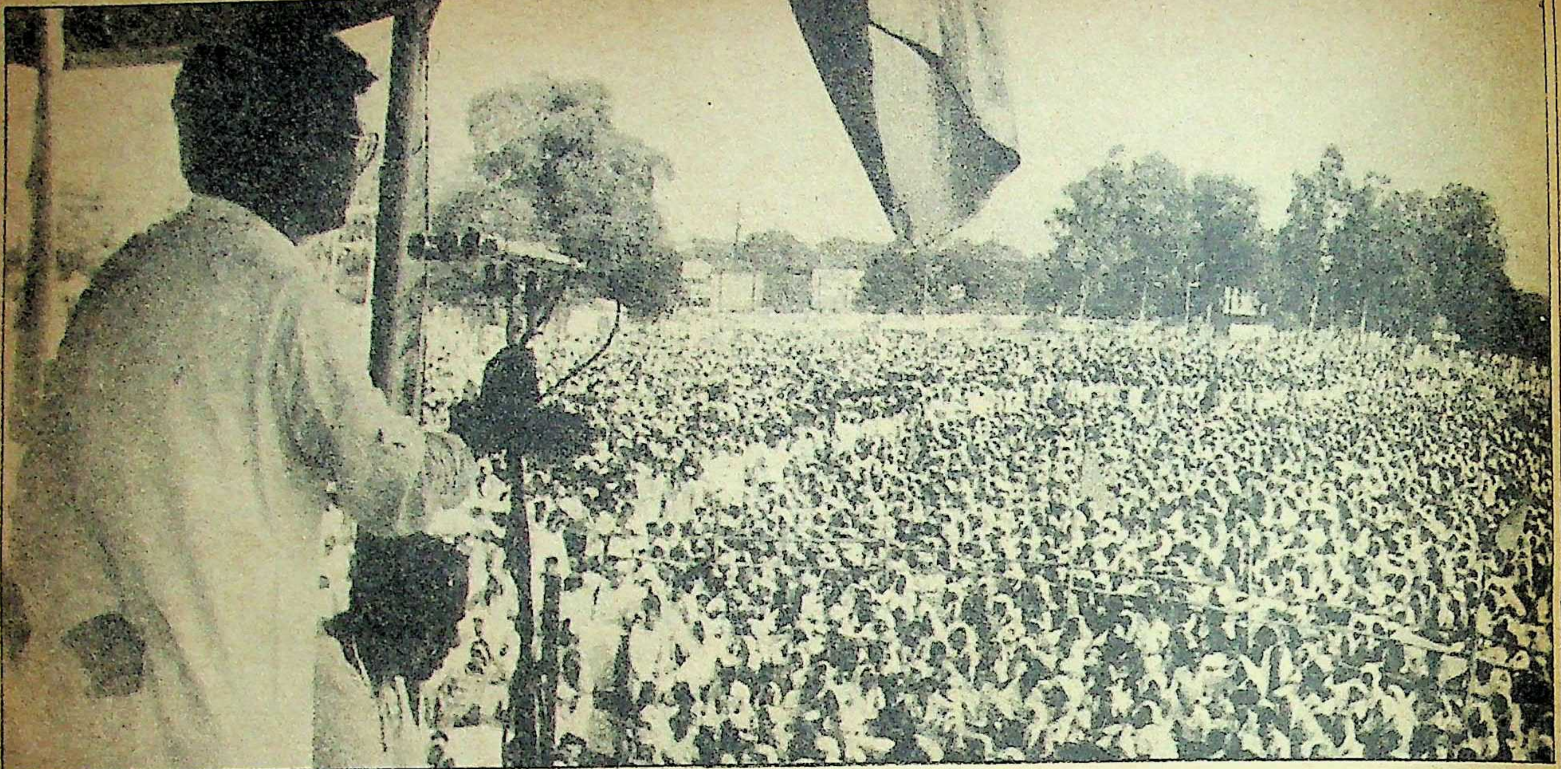

एक लाख रुपए की थैली: अजीत सिंह भाषण देते हुए

दौरान १५ सितम्बर को राज्य कर्मचारी महासंघ ने लखनऊ में रैली की और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। वीर बहादुर सिंह राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों की हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इस हड़ताल का नेतृत्व महासंघ के अगुवा लल्लन पाण्डेय का गुट कर रहा था। शिक्षक विधायक मान्धाता सिंह, वीर बहादुर सिंह के प्रबल विरोधी और वी०पी० सिंह के समर्थक हैं। लल्लन पाण्डेय, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और वी०पी० सिंह समर्थक हैं। लल्लन पाण्डेय ने ही वी०पी० सिंह और कमलापति त्रिपाठी की मुलाकात कराने के लिए मध्यस्थता की थी। कर्मचारी-शिक्षक महासंघ का कहना है कि नवम्बर, १९८६ में आन्दोलनरत कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन देने के लिए मुख्यमंत्री ने जो वेतन समिति गठित की थी, उसे छह माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस समिति द्वारा रिपोर्ट देने में अनावश्यक विलम्ब के कारण हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा।

रैलियों के बहाने थैलियां: अजीत सिंह की मेरठ से लखनऊ तक १२ जनपदों की ७०० किलोमीटर लंबी पदयात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सफल रही। मेरठ में जब उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की, तो 'क्रान्तिकारी मोर्चा' को समर्थन देने वाली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर भी उनके साथ थे। मुलायम सिंह यादव के 'क्रान्ति रथ' के बारे में अजीत सिंह कहते हैं, "क्रान्ति, रथयात्रा से नहीं पदयात्रा से होगी।"

१२ अक्तूबर को लखनऊ के बेगम हजरतमहल पार्क में आयोजित लोकदल-अ की सभा में अजीत सिंह के समर्थक एक लाख की भीड़ जुटाने में सफल हो गये। इस भीड़ का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का था। अजीत सिंह के समर्थन में लोकदल-अ के राष्ट्रीय महासचिव रशीद मसूद, सुब्रह्मण्यम स्वामी, सत्य प्रकाश मालवीय, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल सिंह यादव मौजूद थे। इस रैली में अजीत सिंह को युवा लोकदल की ओर से एक लाख की थैली भेंट की गयी। अजीत सिंह का कहना था कि लोकदल-अ के कार्यकर्ताओं को व्यवस्था परिवर्तन के लिए गांव-गांव पदयात्रा करनी चाहिए और रिश्वतखोरों का घेराव करना चाहिए।

जिस समय अजीत सिंह की सभा चल रही थी, उस समय मुलायम सिंह यादव अर्थात लोकदल-ब के समर्थक शहर भर में लाउडस्पीकर पर १५ अक्तूबर की रैली सफल बनाने का प्रचार कर रहे थे।

अगले ही दिन १३ अक्तूबर को इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने 'राजीव हटाओ' अभियान के तहत रैली व प्रदर्शन किया। १३ अक्तूबर को ही सत्ता परिवर्तन का नारा लगाने वाले मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के डालीगंज में एक सभा कर शहर में एक माफिया सरगना अरुण कुमार शुक्ल उर्फ अन्ना को अपने दल में शामिल करने की घोषणा की। इसके बदले में अन्ना ने व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की ओर से मुलायम सिंह यादव को एक लाख एक हजार रुपए की थैली भेंट की।

उधर अजीत सिंह की रैली को मुलायम सिंह यादव ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर उससे अधिक भीड़ जुटाने का निर्णय किया।

क्रान्तिकारी मोर्चा १५ अक्तूबर को बेगम हजरत महल पार्क में ढाई लाख की भीड़ जुटाने में सफल तो रहा, किन्तु लोकदल-अ जैसा प्रभाव छोड़ने में असफल रहा। क्रांतिकारी मोर्चे की इस सभा में लोकदल-ब, जनता पार्टी, संजय मंच, जनवादी पार्टी, कांग्रेस-ज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आने पर इतनी भीड़ जुट सकी थी। अधिसंख्य लोग आसपास के जिलों से बसों पर लाद कर लाये गये थे, जबकि लोकदल-अ की रैली में गाजियाबाद से बलिया तक के लोग स्वतः आये थे। लोकदल-अ की इस सफलता ने जनता पार्टी और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को पसोपेश में डाल दिया है।

क्रान्तिकारी मोर्चे की सभा में लोकदल-ब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर, संजय मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेनका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, राजस्थान लोकदल-ब के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा, हरियाणा लोकदल-ब के अध्यक्ष ओम प्रकाश सहित कम्युनिस्ट नेता ई०एम०एस० नम्बूदरीपाद, राजेश्वर राव और सरदार सुरजीत सरीखे राष्ट्रीय नेता जुटे थे। सभी नेता विपक्षी एकता के प्रति चिंतित दिखायी दिये। सम्भवतः उन्हें भय है कि क्रांतिकारी मोर्चा कहीं १९७९ की जनता पार्टी की तरह बिखर न जाये।

इस सभा में क्रान्तिकारी मोर्चे ने एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग कर नये चुनाव कराने की मांग की। साथ ही २८ दिसम्बर को 'प्रदेश बंद' की घोषणा कर जनसंघर्ष कार्यक्रम का ऐलान किया। जहां लोकदल का पांच सूत्रीय कार्यक्रम था, वहीं क्रान्तिकारी मोर्चा अपने २१ सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। क्रान्तिकारी मोर्चे की सभा से लोगों का ध्यान हटाने

के लिए युवा लोकदल-अ के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय भवन में कई पटाखे दागे, जिससे सचिवालय में दहशत फैल गयी और चर्चा का विषय क्रान्तिकारी मोर्चे की सभा के स्थान पर बम विस्फोट बन गया।

मुलायम सिंह यादव का दावा है, ''हमें देवीलाल के 'विजय रथ' और एन०टी० रामाराव के 'चैतन्य रथ' का जनसमर्थन मिल रहा है। मैं जनता से एक वोट और एक नोट मांग रहा हूं।''

इन रैलियों—पदयात्रा तथा रथयात्राओं के बारे में वीर बहादुर सिंह का कहना है, ''क्रांति, न तो पदयात्रा से होती है और न ही रथयात्रा से। क्रांति, काम तथा जनता की सेवा से होती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब प्रदेश सूखे की समस्या से जूझ रहा है, किसी को यह फिक्र नहीं है कि वह सूखे से निपटने के लिए सुझाव दे। ऐसी कठिन घड़ी में सरकार की मदद करने के स्थान पर ११ लाख के वातानुकूलित रथ पर यात्रा करने से क्या क्रांति होगी?''

विपक्षी जमावड़ा: मंच पर हेमवती नंदन बहुगुणा, चंद्रशेखर, रामकृष्ण हेगड़े, कर्पूरी ठाकुर आदि

उत्तर प्रदेश के कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह का कहना है, ''मैं जनता के बीच यही कहता हूं कि मेरे एक छोटे भाई हैं, जो उस देश में पैदा हुए हैं जहां का किसान भी अपने खेत में हेलीकाप्टर से उतरता है। उस संस्कृति में पले-बढ़े मेरे भाई पदयात्रा कर रहे हैं।

''मेरे एक दोस्त हैं, जो सूखे के समय ११ लाख के वातानुकूलित रथ पर सवार होकर जनता से वोट और नोट मांग रहे हैं।

''मेरे तीसरे बड़े भाई एक समय कहते थे कि नेहरू परिवार सोने की खान है उससे तो हमेशा सोना ही निकलेगा, लेकिन आज उनके अनुसार सोने की जगह कोयला निकल रहा है। वह रैलियों और सभाओं के जरिये सूखे में जनता को राहत देने के स्थान पर जनता को गुमराह कर रहे हैं।''

क्रांतिकारी मोर्चे की सभा में ६ लाख रुपए की थैलियां मुलायम सिंह यादव को मिलीं। इसी प्रकार अजीत सिंह को भी एक लाख की थैली मिली। कुल मिलाकर ये रैलियां, थैलियां बटोरने की ही होकर रह गयीं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्रांतिकारी मोर्चा तथा लोकदल-अ की रैली में बसों पर लोगों को लाने में जो रुपए खर्च हुए वे कहां से आये? क्या यह उचित नहीं था कि रैलियों के नाम पर जो लाखों रुपए खर्च किये गये, उसे गरीब सूखा पीड़ित किसानों की मदद में खर्च किया जाता।

प्रदेश की राजधानी में हुई रैलियों में ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता तथा कृषकों को कर्ज माफ करने का सब्जबाग दिखा कर लाया गया था। लोकदल-अ के नेताओं ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए किसानों से जबानी वादा किया था कि उनके कर्ज हरियाणा की तरह माफ कर दिये जायेंगे। यह देख क्रांतिकारी मोर्चे की ओर से लोकदल-ब ने कर्जे माफ कराने सम्बन्धी फार्म भरवाने शुरू कर दिये थे। फार्मों में लिखा है कि हम कर्ज से पीड़ित कृषक लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार हरियाणा में लोकदल-ब की सरकार ने ग्रामीण कृषकों पर बकाया २० हजार रुपयों तक के सभी सरकारी कर्जों को माफ कर दिया है, उसी प्रकार हमारे ऊपर बकाया सरकारी कर्जे माफ किये जायें। ठीक इसी तर्ज पर लोकदल-ब ने बेरोजगार युवकों से भी फार्म यह कह कर भरवाये थे कि सरकार उन्हें १०० रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। किसानों के मन में यह बात भी बैठायी गयी कि कांग्रेस-इ सरकार किसान विरोधी है। वह नहीं चाहती कि किसानों के कर्जे माफ हों। इसी कारण लोकदल-ब को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों में यह भावना भी पैदा की जा रही है कि देवीलाल ने हरियाणा में किसानों के कर्जे माफ कराने के लिए दो साल तक संघर्ष किया था। यदि लोकदल-ब द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन में उत्तर प्रदेश के किसान भाग लेते रहे, तो उनके कर्ज भी अवश्य माफ हो जायेंगे। क्रांतिकारी मोर्चे की आड़ में लोकदल-ब के नेताओं ने टिकैत की तर्ज पर किसानों को सरकारी कर्ज न चुकाने के लिए भड़काना शुरू कर दिया है।

मतभेदों की शुरुआत: इन सब के बावजूद क्रान्तिकारी मोर्चे के नेताओं में मतभेदों की शुरुआत हो गयी है। क्रान्तिकारी मोर्चे में शामिल साम्यवादी दल के नेता सरजू पाण्डेय का कहना है, ''लोकदल-ब ने आंदोलन के लिए जो मुद्दे तैयार किये हैं उनमें कई ऐसी मांगे शामिल कर दी गयी हैं, जिनके बारे में न तो हमारे दल की सहमति ली गयी और न ही हमें कुछ जानकारी है। मैंने १३ अक्तूबर को लोकदल-ब के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना विरोध प्रकट किया था। उस समय लोकदल-ब के नेताओं ने मांग-पत्र न वितरित करने का वायदा किया था। इस मांग पत्र को १५ अक्तूबर की रैली में बांटकर लोकदल-ब ने वचन भंग किया है।''

क्रांतिकारी मोर्चे में माफिया सरगना अरुण शुक्ल उर्फ अन्ना द्वारा १३ अक्तूबर को डालीगंज में सभा आयोजित करने और मुलायम सिंह यादव द्वारा उसे राजनीतिक संरक्षण देने के प्रश्न पर काफी मतभेद हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव का कहना है, ''अन्ना ने मेरे सामने भविष्य में कोई अपराध न करने की कसम खायी है।'' मुलायम सिंह के अनुसार देश के बड़े-बड़े नेताओं की राय थी कि आदमी से नहीं उसके काम से घृणा की जानी चाहिए। इधर क्रांतिकारी मोर्चे के कुछ नेताओं का कहना है कि अन्ना पुलिस रिकार्ड में 'ए' दर्जे का अपराधी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गिरोह बंदी कानून में वह तीन बार पकड़ा जा चुका है। उसकी हिस्ट्रीशीट भी खुली हुई है। ऐसे व्यक्ति को क्रांतिकारी मोर्चे में लेकर मुलायम सिंह यादव अपराध का राजनीतिकरण कर रहे हैं। यदि यही हालत रही, तो हमें गुंडों के मोर्चे से अलग होने पर मजबूर होना पड़ेगा।

लोकदल-अ में भी विधानभवन परिसर में युवा लोकदल-अ के कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे छोड़ने की घटना को लेकर आपाधापी मची हुई है। पटाखे छोड़ने वाले दल का नेतृत्व युवा लोकदल-अ के प्रदेश अध्यक्ष गंगाचरण राजपूत कर रहे थे। गंगाचरण के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

अभी तक सिर्फ युवा लोकदल-अ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के इंचार्ज इलाहाबाद से विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने 'पटाखा कांड' पर अपना मुंह खोला है। उनके अनुसार, ''कुछ दल क्रांति का भ्रम फैलाकर 'सूखा राहत में धांधली' आदि जैसे जरूरी मुद्दों को अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में सोयी हुई सरकार को जगाने के लिए पटाखे जरूरी हो गये थे।'' लोकदल-अ के वरिष्ठ नेता इस घटना का न तो समर्थन कर पा रहे हैं और न विरोध ही। विधानसभा में विपक्ष के नेता लोकदल-अ के सत्यपाल यादव भी इस घटना का विरोध करने से कतरा रहे हैं।

१५ अक्तूबर को जब क्रांतिकारी मोर्चे की बेगम हजरत महल पार्क में सभा चल रही थी, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह लखनऊ में ही मौजूद थे। वी०पी० सिंह अपने निवास पर इस इंतजार में बैठे थे कि संभवतः उन्हें भी सभा को संबोधित करने के लिए रैली में बुलाया जायेगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

—निशीथ जोशी

रैलियों की राजनीति

विपक्षी दलों द्वारा आयोजित रैलियों और उनकी व्यापक सफलता से प्रभावित होकर लगता है वीर बहादुर सिंह ने भी रैलियों का जवाब रैलियों से देने की ठान ली है। हालांकि इन रैलियों का आयोजन उन्होंने 'सूखा संकट' से निपटने के नाम पर किया, मगर मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की रैलियों में साफ हो गया कि उनका मुख्य निशाना वी०पी० सिंह ही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-इ सरकार रैलियों के बल पर वी०पी० सिंह के असर को कम कर सकेगी?

रैली का जवाब रैली: मुजफ्फरनगर में कांग्रेस-इ रैली में सरकारी साधनों से जुटी भीड़

विपक्ष के रैली अभियान से बौखलाकर उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ दल ने भी अंततः दो-दो हाथ करने की ठान ही ली। 'रैली का जवाब रैली से' की तर्ज पर मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में दो बड़ी रैलियां आयोजित करवा डालीं। यों तो इन रैलियों का आयोजन सूखे की समस्या से निपटने और राहत कार्यों में तेजी लाने के नाम पर किया गया था, मगर नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों से असल मंशा साफ जाहिर हो गया। अब इसमें शक नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश इंका ने मंडल स्तर पर रैलियों के आयोजन के साथ वी०पी० सिंह पर जवाबी हमले और उनकी सभाओं में हंगामा कराने का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। उन्नाव और कानपुर में जहां इंकाइयों ने राजा की सभाओं में जमकर उत्पात किया, वहीं मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर की इंका रैलियों में उनकी चौकड़ी के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। इन रैलियों में एक नया नारा भी दिया गया, 'राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है।'

बहरहाल, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह इन रैलियों की सफलता से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार, "यू०पी० में अब राजा का कोई वजूद नहीं रहा। वह और उनका जनमोर्चा, मेनका गांधी और उनके संजय मंच की तरह खतम हो रहा है।"

रैली के बहाने राजा पर हमला: १७ अक्तूबर को मुरादाबाद मंडल के इंकाइयों की रैली मुरादाबाद में आयोजित की गयी थी। इस रैली में सरकारी साधनों का भरपूर उपयोग कर ७०-८० हजार की भीड़ इकट्ठी की गयी थी। इस रैली में केन्द्रीय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी, शहरी आवास मंत्री मोहसिना किदवई, इंका के तीन अखिल भारतीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, केदारनाथ सिंह और नरेश चन्द्र चतुर्वेदी के अलावा वीर बहादुर सिंह ने भी भाग लिया। रैली में सूखे की समस्या और उसके समाधान का कोई खास उल्लेख किसी वक्ता ने नहीं किया। हां सभी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ल और आरिफ मोहम्मद खां के 'कारनामों' का खुलासा करते हुए यहां तक कह दिया, "ये लोग विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं।" गुलाम नबी आजाद ने तो साफ आरोप लगाया, "इस मुल्क के राजे-महाराजे कभी भी देश भक्त रहे ही नहीं। आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का खुलकर साथ दिया था" (हालांकि यह कहकर उन्होंने अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया पर भी आरोप लगा दिया)। इस रैली में वीर बहादुर सिंह तो यहां तक कह गये, "जो राजा, कुछ महीने पहले तक अरुण नेहरू को इस देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति कहता था, आज उसी राजा की नजर में अरुण नेहरू सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं।"

कहीं यह रैली राजा को गाली देनेवाली रैली बनकर न रह जाये, इसलिए वीर बहादुर सिंह ने वहां कुछ घोषणाएं भी कीं। मसलन, सूखे से प्रभावित सभी जरूरतमंदों को रोजगार दिया जायेगा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक करोड़, २७ लाख रुपए खर्च किये जायेंगे। गांवों में १० घंटे बिजली दी जायेगी। इसी के साथ ही मुरादाबाद जिले को सूखा राहत के लिए ५ करोड़, १७ लाख रुपए दिये गये हैं।

मुरादाबाद की रैली के दो दिनों बाद यानी १९ अक्तूबर को मेरठ मंडल के इंकाइयों की रैली मुजफ्फरनगर में आयोजित की गयी। रैली के लिए मुजफ्फरनगर जिले के चयन के पीछे कई कारण थे। पहला कारण यह था कि राजा मांडा ने पार्टी से अपना इस्तीफा मुजफ्फरनगर से भेजा था और यहीं उन्होंने राजीव गांधी के विरुद्ध सबसे पहली रैली की थी। दूसरा कारण यह था कि राजा के पार्टी से हटते ही मुजफ्फरनगर इंका की पूरी जिला इकाई राजा के साथ हो गयी थी। तीसरा और सबसे मुख्य कारण था कि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाके में किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत के बढ़ते प्रभाव को कम किया जाये।

वीर बहादुर सिंह को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि स्थानीय इंकाइयों के भरोसे यह रैली सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले के सभी इंका विधायकों और नेताओं के अपने-अपने अलग गुट हैं। एक गुट दूसरे गुट को फूटी आंख नहीं सुहाता है। यही वजह थी कि रैली के आयोजन की तारीख १२ अक्तूबर को बदलकर १९ अक्तूबर करनी पड़ी। वास्तव में, जब मुजफ्फरनगर के सबसे शक्तिशाली और धनी नेता विद्याभूषण ने १२ अक्तूबर की रैली के आयोजन से अपना हाथ खींच लिया, तो वीर बहादुर सिंह ने उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया, "अब जैसे भी हो १९ अक्तूबर की रैली सफल होनी चाहिए।" स्थानीय नेताओं की गुटबंदी को दूर करने की जिम्मेदारी बहराइच के इंका सांसद तथा पार्टी के प्रादेशिक महामंत्री राणा वीर सिंह पर सौंपी गयी।

इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने घोषणा कर दी, "हम न तो कांग्रेस की रैली होने देंगे और न ही २३ अक्तूबर को राजा की रैली। यूनियन के लोग मुजफ्फरनगर जाने वाली सभी सड़कें जाम कर देंगे तथा किसी भी

मंत्री और नेता को शहर में घुसने नहीं देंगे।" टिकैत की इस घोषणा से रैली के आयोजकों के हाथ-पैर फूल गये। बहरहाल, टिकैत से निपटने की जिम्मेदारी विद्याभूषण ने अपने हाथ में ले ली। गांव-गांव के 'नामी-गरामी' लोगों को उन्होंने टिकैत और उनके साथियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। टिकैत के प्रभाव वाले क्षेत्र कैराना से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यमंत्री हुकुम सिंह से जिले के अधिकांश इंका कार्यकर्ता रुष्ट थे। यही वजह थी कि हुकुम सिंह रैली के लिए लोगों को एकत्र करने गांवों में नहीं घुस सके।

उधर महेन्द्र सिंह टिकैत ने जब यह देखा कि विद्याभूषण ने उनका मुकाबला करने के लिए 'लट्ठबाजों' की फौज तैयार कर ली है, तो रैली के एक दिन पूर्व टिकैत ने अपना विरोध वापस लेते हुए कहा, "हम किसानों को मारपीट से दूर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश भी पंजाब बन जाये, इसलिए रैली में जाने वाले लोगों को बलात रोकने का निर्णय किसान यूनियन वापस लेती है।" इसी के साथ टिकैत ने यह घोषणा भी की, "हम रैली के बहिष्कार के निर्णय पर अडिग हैं, जो किसान उसमें शामिल होगा वह 'गद्दार' माना जायेगा और हम उसे किसान यूनियन से निष्कासित कर देंगे।"

टिकैत ने यह निर्णय १८ अक्तूबर को शामली (मुजफ्फरनगर) में आयोजित किसानों की एक सभा में लिया। इस सभा में ज्यादातर किसान इस पक्ष में थे कि टिकैत अपने पूर्व निर्णय को न बदलें। यही वजह थी कि जब टिकैत ने अपने पूर्व निर्णय को वापस लेने की घोषणा की, तो अधिकांश किसान सभा से उठकर चले गये। इस सभा में टिकैत ने विद्याभूषण को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुण्डा बताते हुए कहा, "उससे टकराने का मतलब है निर्दोष किसानों का खून-खराबा कराना।"

अगले दिन इंका की रैली राजकीय इंटर कालेज के ग्राउंड पर हुई। सरकारी साधनों के बल पर वहां करीब ८० हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी की गयी थी। पूरा शहर झंडे और बैनरों से सजाया गया था। इस सजावट पर करीब पांच लाख रुपए का खर्च आया, जिसका काफी हिस्सा विद्याभूषण ने खर्च किया था। इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है कि ज्यादातर बैनर और तोरणद्वारों पर लिखा था, 'विद्याभूषण के सौजन्य से।'

दोपहर लगभग डेढ़ बजे वीर बहादुर सिंह हेलीकाप्टर द्वारा पुलिस लाइन में उतरे। उनके साथ केदारनाथ सिंह और नरेश चन्द्र चतुर्वेदी भी आये थे, जबकि मोहसिना किदवई और गुलाम नबी आजाद सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह रैली शुरू हो जाने के बाद पहुंचे। हेलीपैड से जब मुख्यमंत्री का काफिला रैली स्थल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में स्थानीय वकीलों ने वीर बहादुर सिंह की कार को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग कर रहे थे। वकीलों का कहना था मुख्यमंत्री कार से उतरकर उनसे ज्ञापन लें। वीर बहादुर सिंह कार से उतरकर जब उन तक पहुंचे, तो वकीलों ने दुर्व्यवहार किया। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर वकीलों को खदेड़ दिया। बाद में वीर बहादुर सिंह ने कहा, "प्रदर्शनकारी वकील लोकदल के कार्यकर्ता थे।"

यह पहले ही तय हो चुका था कि मुजफ्फरनगर में इंका की गुटबंदी को देखते हुए किसी भी स्थानीय नेता को मंच से नहीं बोलने दिया जायेगा। पहला भाषण केदारनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने राजा और उनके समर्थकों को जमकर बुरा-भला कहा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद बोले, "जो राजा डाकुओं के डर से मुख्यमंत्री की कुरसी छोड़कर भाग सकता है, वह इस देश को कैसे चला सकता है। यही राजा कहते थे, अरुण नेहरू, राजीव गांधी को किसी से मिलने नहीं देता। वह खूब पैसे कमा रहा है, मगर आज वही अरुण नेहरू उसी राजा के सबसे विश्वासपात्र हैं। इसी तरह विद्याचरण शुक्ल आज राजा के लिए सबसे ज्यादा 'दूध के धोये' हो गये हैं।"

इसी रैली में इंका के महामंत्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने एक नया नारा देते हुए कहा, "राजा के लोग कहते हैं, 'राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है,' लेकिन मैं कहता हूं, 'राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है'।"

वीर बहादुर सिंह ने राजा और उनके समर्थकों को किसान विरोधी बताते हुए कहा, "किसानों का असली हितैषी मैं हूं, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। किसानों की क्या तकलीफें हैं, मैं जानता हूं। किसानों को गन्ने का मूल्य कम मिल रहा है, इसलिए मैं उसे बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ग्रामीण इलाकों में औसतन दस घंटे बिजली मिलेगी, इसका आश्वासन देता हूं। इस विशाल रैली ने यह साबित कर दिया है कि इस देश का किसान राजीव गांधी के साथ है।"

अगर रैली के संयोजक राणा वीर सिंह थोड़ी गलती न कर देते, तो यह रैली पूरी तरह सफल कही जाती। हुआ यह, कि जब मंच से उन्होंने राज्यमंत्री हुकुम सिंह की तारीफ कर दी, तो दूसरे गुट के इंकाई रैली से उठकर जाने लगे। जब वीर बहादुर सिंह बोल रहे थे, तो आधे से भी ज्यादा भीड़ छट चुकी थी। इसके पूर्व भी जब रैली में शामिल लोगों को हुकुम सिंह समर्थक इंकाई ऐसी टोपी बांटने लगे, जिस पर हुकुम सिंह का नाम छपा था, तो विद्याभूषण गुट के समर्थक तथा पूर्व विधायक नकली सिंह ने इस 'टोपी वितरण' का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने राणावीर सिंह से यहां तक कह दिया था कि अगर टोपी बंटना बंद नहीं हुई, तो हमारे लोग रैली का बहिष्कार कर देंगे;

> **रैली में इंका महामंत्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने एक नया नारा देते हुए कहा, "राजा के लोग कहते हैं, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, लेकिन मैं कहता हूं, 'राजा नहीं रंक' है, देश का कलंक है।"**

रैली की समाप्ति के बाद एक और घटना घटी, जिसके कारण मुजफ्फरनगर के इंकाइयों की गुटबंदी बीच सड़क पर आ गयी। जब वीर बहादुर सिंह रैली समाप्त कर दिल्ली जाने के लिए हेलीपैड पर पहुंचे, तो एक स्थानीय इंका विधायक सईदुज्जमा ने मुख्यमंत्री से कहा, "आपको मेरे घर चलकर चाय पीनी पड़ेगी। मैंने वहां इन्तजाम कर रखा है और तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं।" वीर बहादुर सिंह जब वहां चलने के लिए तैयार हो गये, तो जिलाधिकारी अरुण कुमार विट और पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्रनाथ सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्रीजी, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। रास्ते में रैली से वापस हो रही भीड़ के कारण मार्ग अवरुद्ध हैं।" अधिकारियों की सलाह मानकर वीर बहादुर सिंह ने चाय पर जाने से इनकार किया, पर सईदुज्जमा जिद्द करने लगे। मोहसिना किदवई और गुलाम नबी आजाद ने भी सईदुज्जमा का पक्ष लिया, नतीजतन वीर बहादुर को उनके घर चाय पर जाना पड़ा। जैसे ही वीर बहादुर सिंह सईदुज्जमा के घर पहुंचे, बाहर खड़े करीब ३०-४० इंकाइयों ने नारेबाजी शुरू कर दी, "चंदे की चाय नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री वापस जाओ।" यह बवाल देख वीर बहादुर सिंह जल्दी-जल्दी चाय पीकर वापस चले गये। नारेबाजी कर रहे इंकाइयों का आरोप था कि विधायक ने मुख्यमंत्री को अपने घर पर चाय पिलाने के लिए स्थानीय व्यापारियों से काफी चंदा वसूला है, जबकि सईदुज्जमा का कहना था यह आरोप दूसरे गुट के लोग लगा रहे हैं। मैंने चाय के लिए अपनी जेब से दस हजार रुपए खर्च किये हैं, किसी से चन्दा-वन्दा नहीं लिया है।

जब विद्याभूषण गुट के लोगों तक यह खबर पहुंची कि वीर बहादुर सिंह, सईदुज्जमा के यहां गये थे तो विधायक नकली सिंह विद्याभूषण पर बरस पड़े, "वीर बहादुर आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। पहले से पता होता कि वह यहां आकर दूसरे गुट को बढ़ावा देंगे, तो हम कतई यह रैली सफल न होने देते। आपने बेकार अपना चार-पांच लाख खर्च कर दिया।" विद्याभूषण हंस कर टाल गये, "दोस्ती में यह सब चलता रहता है।" ठीक इसी तरह की रैली आगरा और फतेहपुर में भी आयोजित की गयी।

—मुजफ्फरनगर से, अजय कुमार

साक्षात्कार/जामिनी दिस्सानायक

भारत को तमिलों से हर कीमत पर हथियार डलवाने चाहिए

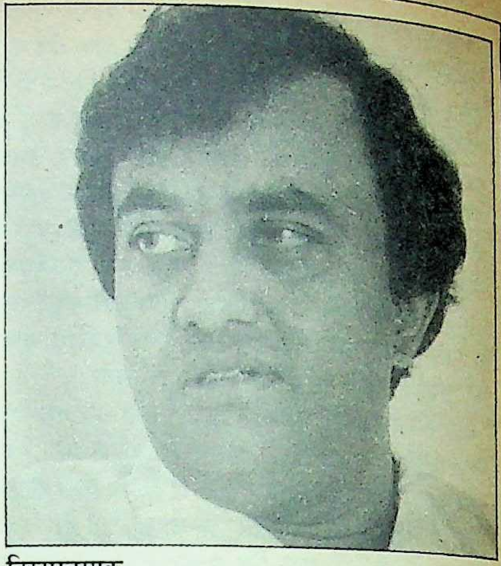

दिस्सानायक

जब ऐतिहासिक भारत-श्रीलंका समझौते पर गत जुलाई में हस्ताक्षर हुए, तो यह समझा गया कि यह राजीव गांधी की १९८७ की एकमात्र ऐसी उपलब्धि है, जिस पर राजनीतिक कौशल की मुहर लगी है। भाजपा के थोड़े से विपक्षी नेताओं और कुछ सत्ताविरोधी बुद्धिजीवियों को छोड़कर इस देश के बहुसंख्य लोगों ने इसे श्रीलंका में टिकाऊ शांति स्थापना के लिए 'समय पर उठाया' और 'सही' कदम करार देते हुए इस समझौते का स्वागत किया।

बहरहाल, सुखानुभूति की भ्रांति ज्यादा दिन नहीं रही। समझौते की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और इसके प्रशंसक अब आलोचक में बदल गये हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि अब तमिल आतंकवादियों के प्रहार का निशाना श्रीलंका सेना की जगह भारतीय शांति सेना है और भारत सरकार ने जहां शांति सेना के हताहतों की सही संख्या बताने में अनिच्छा व्यक्त की है, वहीं पश्चिमी पत्रकारों के अनुसार यह संख्या ५०० पार कर गयी है। पहली बार स्वतंत्र भारत की सेनाएं विदेशी धरती पर और एक विदेशी सरकार के निर्देशों पर युद्ध कर रही हैं। सबसे बदतर स्थिति तो यह है कि श्रीलंका के स्थान पर भारत सरकार इस कार्यवाही का खर्च वहन कर रही है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना हर रोज एक करोड़ रुपए श्रीलंका में खर्च कर रही है।

इस सबको देखते हुए प्रश्न उठता है, क्या श्रीलंका के मसले में भारत का उलझना उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण था? क्या भारत को कोई लाभ हुआ है? क्या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हुई है? लोगों का मत है कि यदि भारत ऐसा न करता, तो अब तक पाकिस्तानी सेनाएं श्रीलंका में होतीं और उसकी उपस्थिति से हमें नुकसान होता।

यह तर्क भी दिया जा रहा है कि जब भारत बंगला देश के संकट में उलझा था, तो यह निर्णय अलोकप्रिय माना जा रहा था, किन्तु बाद में लोगों से उसकी खूबी का एहसास हुआ और ऐसा ही श्रीलंका के मामले में होगा। किन्तु दोनों स्थितियों में बुनियादी अंतर है। १९७१ में बंगला देश पाकिस्तान का एक भाग था और इस प्रकार यह संकट उसका आंतरिक मामला था, इसलिए भारत ने मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने स्पष्ट रूप से 'मुक्ति वाहिनी' का साथ दिया, साथ मिलकर युद्ध किया और अंततः विजयश्री मिली।

इसके विपरीत श्रीलंका में भारत की एक मध्यस्थ की भूमिका है। यदि ऐसा ही है, तो उसे न केवल मध्यस्थ जैसा काम करना चाहिए, बल्कि उसकी ऐसी छवि भी होनी चाहिए। किन्तु क्या ऐसा हुआ है?

पहली बात तो यह है—समझौते पर तमिल उग्रपंथियों और श्रीलंका सरकार के हस्ताक्षर नहीं थे। यह समझौता भारत सरकार और श्रीलंका के बीच हुआ था। मानो विवाद इन्हीं दोनों पक्षों के बीच हो। दूसरे, जिन तमिलों की भलाई के लिए भारत श्रीलंका गया—जैसाकि सरकार दावा करती है—वही अब इस देश के खिलाफ हैं और युद्ध छेड़े हुए हैं।

दूसरी ओर, बहुसंख्यक सिंहली भारत की भूमिका के प्रशंसक नहीं हैं। जनता विमुक्ति पेरामुना के बौद्धों और दक्षिणपंथी आतंकवादियों ने भारत की खुल्लमखुल्ला निंदा की है। इसके साथ ही शासक युनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख सदस्यों, जिसमें प्रधानमंत्री प्रेमदास शामिल हैं, का भी यही रवैया है। इस तरह भारत ने किसको संतुष्ट किया है? अनेक लोगों का विश्वास है कि केवल राष्ट्रपति जयवर्धने और उनकी सरकार ही गत जुलाई के समझौते से लाभान्वित हुई है जैसाकि पश्चिमी पत्रकारों की हाल की रिपोर्टों से पता चलता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना को तमिल समस्या हल करने के लिए नहीं बल्कि अपने शासन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए बुलाया था। अगर वह ऐसा न करते, तो उनकी सरकार को बढ़ते सैनिक विद्रोह का सामना करना पड़ता और अंततः तख्ता पलट जाता।

तमिलनाडु के लोग इस स्थिति का किस प्रकार आकलन करतें हैं यह भी महत्वपूर्ण है। दरअसल, यही आंतरिक मुद्दा-अर्थात तमिलनाडु की राजनीति श्रीलंका जाने के पहले, श्री गांधी के दिमाग का बोझ बनी हुई थी। यह आशंका थी कि यदि केन्द्र ने श्रीलंका के तमिलों की रक्षा के लिए मजबूत कदम न उठाया, तो तमिलनाडु के लोग विद्रोह कर देंगे और देश में इससे एक और पृथकतावादी आंदोलन पैदा हो जायेगा। इसी कारण श्री गांधी ने फैसले के हर स्तर पर शासक दल अन्नाद्रमुक को शामिल किया। पर अब जबकि भारतीय सेना उनकी (श्रीलंका के तमिलों की) हत्या कर रही है, तो क्या तमिलनाडु के राजनीतिज्ञों का पहले जैसा रवैया बरकरार रहेगा? क्या द्रमुक कार्यकर्ताओं को शांत किया जा सकेगा?

इन सवालों का जवाब केवल समय ही

शांति-सेना उपकरणों को ले जाते हुए

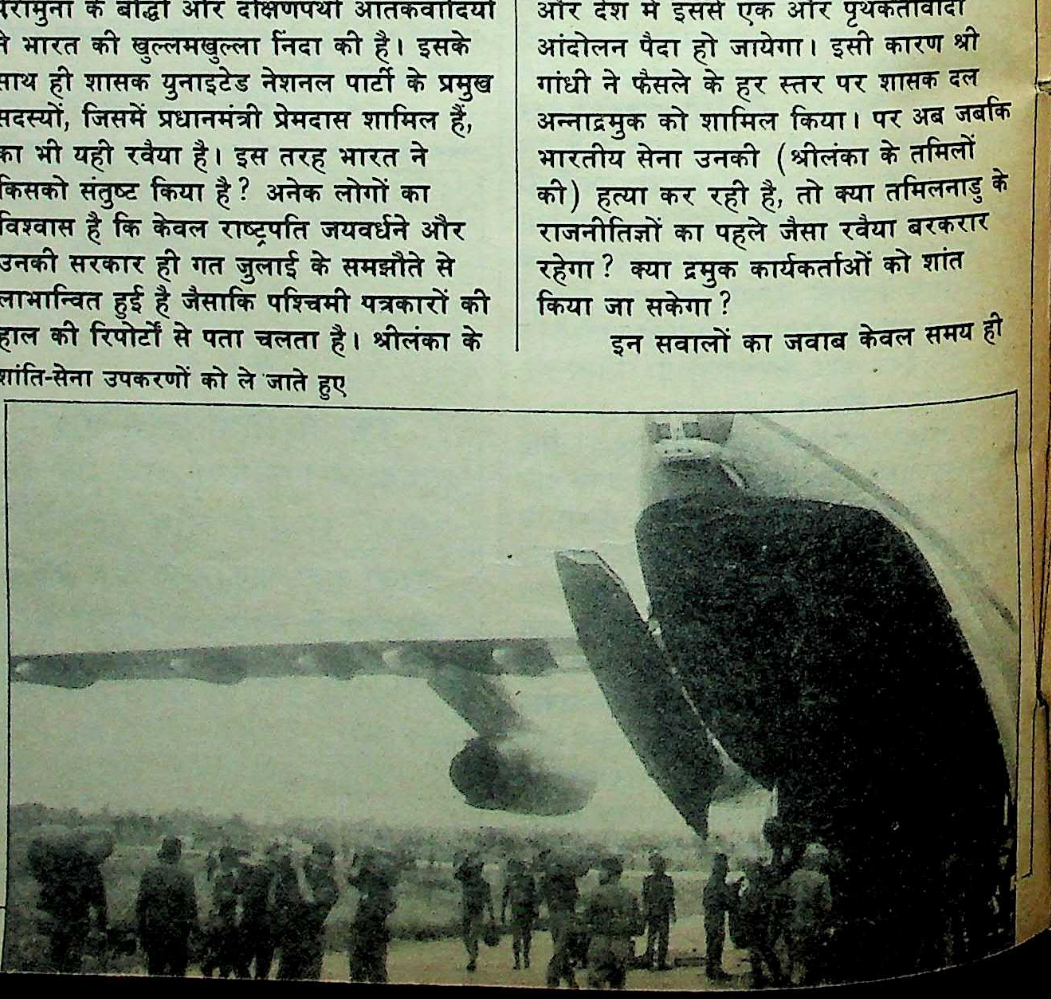

दे सकेगा, किन्तु ऐसा निराशाजनक माहौल इन दिनों बन गया है जिससे लोग कहने लगे हैं कि जुलाई के समझौते पर गलत लोगों ने, गलत लक्ष्य के लिए और गलत समय पर हस्ताक्षर किये थे। बहरहाल जामिनी दिस्सानायक, जोकि श्रीलंका में भूमि और विकास मंत्री हैं और समझौते में जिनकी अहम भूमिका रही है, की ऐसी धारणा नहीं है। दरअसल, वह राष्ट्रपति जयवर्धने के घनिष्ठतम सहयोगी माने जाते हैं और कहा जाता है कि राष्ट्रपति उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। दिस्सानायक मानते हैं कि समझौता जरूर कामयाब होगा। उन्होंने काठमांडू के हाल के दक्षेस वार्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते समय नयी दिल्ली में रुककर 'माया' के प्रकाश नंदा से लगभग दो घंटे तक बातचीत की। युवा और कर्मठ मंत्री बता रहे हैं कि उनकी धारणा की वजह क्या है। प्रस्तुत हैं, बातचीत के अंश:

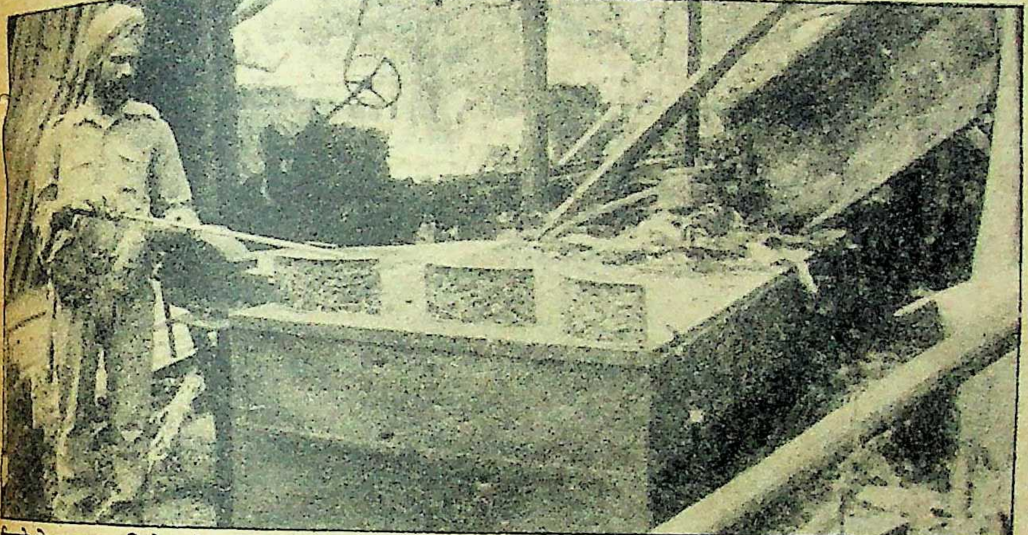

लिट्टे से बरामद किये गये हथियार

माया: भारत-श्रीलंका समझौते की भावी संभावनाएं क्या हैं?

जामिनी: बहुत अच्छी। यह करार, जिसे आप भारतीय समझौता नाम देना पसंद करते हैं, तमिल उग्रवादियों के विरोध के बावजूद लागू किया जायेगा।

माया: आपके इस आशावाद का आधार?

जामिनी: क्योंकि यह करार एक अद्वितीय दस्तावेज है, जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। यह छोटा होते हुए भी अत्यधिक सार्थक और व्यवहारयोग्य है।

माया: यदि ऐसा ही है, तो लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम) इसे नष्ट क्यों करना चाहता है?

जामिनी: इसमें वह सफल नहीं होंगे। करार पर हस्ताक्षर करना एक घाव को दो डाक्टरों-राष्ट्रपति जयवर्धने और प्रधानमंत्री राजीव गांधी-द्वारा आपरेशन करने के समान है, परंतु प्रत्येक सफल आपरेशन की तरह श्रीलंका का घाव भरने में भी थोड़ा समय लगेगा।

माया: परंतु क्या यह सत्य नहीं कि यह समझौता श्रीलंका में बेहद अलोकप्रिय है?

जामिनी: लोकप्रियता पानी के बुलबुले के समान है, अभी यह छोटा है, अगले क्षण यह थोड़ा बड़ा हो सकता है और उसके बाद यह फूट सकता है। इसलिए हम इस समझौते को लोकप्रियता की कसौटी से नहीं नाप सकते। छोटे-मोटे राजनीतिज्ञ इससे प्रभावित हो सकते हैं, किंतु कूटनीतिज्ञ नहीं।

माया: तो क्या आप मानते हैं कि समझौता आपके देश में अलोकप्रिय है?

जामिनी: कहा नहीं जा सकता। यह सच है कि कुछ कट्टर सिंहली, राजनीतिक दल, जैसे एस एल एफ पी (श्रीलंका लिबरेशन फ्रीडम पार्टी), इस समझौते के विरुद्ध हैं। परंतु सिंहलियों का शांत बहुमत इसका समर्थन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

माया: चुनावों व जनमत-संग्रह, जिनका अधिकार श्रीलंकावासियों को अभी मिला है, के अभाव में आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे?

जामिनी: संसदीय लोकतंत्र में आप हमेशा हरेक फैसले से पहले लोगों के पास उनकी रजामंदी के लिए नहीं जा सकते। यह आदर्श केवल किताबों में मिलता है, असली जिंदगी में नहीं। ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों के प्रतिनिधि, जो संसद में हैं, उन्हें जरूरी फैसले लेते समय विश्वास में लिया जाये।

माया: परंतु क्या ऐसा हुआ है? इस समझौते को अभी संसद की सहमति मिलनी बाकी है, हालांकि राष्ट्रपति जयवर्धने ने इसे सितंबर के अंत में अक्तूबर के प्रारंभ तक संसद में पेश करने का वायदा किया था।

जामिनी: यह देरी इसलिए हुई, क्योंकि कुछ नागरिक उच्चतम न्यायालय में चले गये हैं। लोकतंत्र में किसी को न्यायिक चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता। जैसे ही अदालत अपना फैसला देगी, यह मामला संसद में पेश कर दिया जायेगा। वैसे भी वर्तमान संसद की कुल १६० सीटों में से हमारी पार्टी युनाइटेड नेशनल पार्टी (यू एन पी) की १४० सीटें हैं। सो वैसे भी देखा जाये, तो संसद की सहमति लेना महज एक औपचारिकता है।

माया: क्या आपकी पार्टी में सब एकमत हैं?

जामिनी: पार्टी के संसदीय दल ने इस समझौते को सहमति दे दी है और मंत्रिमंडल ने भी ऐसा ही किया है।

माया: यदि ऐसा ही है, तो अपने प्रधानमंत्री प्रेमदास के समझौता-विरोधी वक्तव्यों के बारे में आपका क्या विचार है?

जामिनी: उनके वक्तव्यों से कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वैसे वे उनके निजी विचार हो सकते हैं, किंतु पार्टी या सरकार के नहीं।

माया: क्या आपको विश्वास है कि यह समझौता सफल होगा?

जामिनी: भारत-श्रीलंका समझौता एक विवाह की तरह है, जिसकी सफलता के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना कठिन है। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। विवाह से पहले यह जानना कठिन होता है कि आपका जीवन साथी आपकी आशाओं के अनुरूप है कि नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह एक जोखिम है, किंतु यह उठाना ही चाहिए। इसी प्रकार केवल समय ही बता सकता है कि यह समझौता सफल होगा या नहीं। वैसे मैं दावे से कह सकता हूं कि जब यह कामयाब हो जायेगा, तो लोग हमें शाबाशी देंगे। इसलिए अभी हमारा ध्येय यह देखना है कि यह समझौता सफल हो।

माया: लेकिन क्या विवाह की भांति भारत के साथ यह समझौता श्रीलंका के लिए सर्वोत्तम था?

जामिनी: मैं जीवन की सच्चाइयों में विश्वास करता हूं। ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी को जीवन में सर्वोत्तम ही मिलता हो। सो हमें जो कुछ अच्छा मिलता है, उसी से संतुष्ट होना चाहिए।

माया: क्या आपका कहने का तात्पर्य है कि यह समझौता सबसे बेहतर उपाय नहीं था?

जामिनी: हां, इस जातीय समस्या का समाधान करने का सबसे बेहतर उपाय यही होता कि भारत सरकार निष्पक्ष रूप से अपने देश से तमिल उग्रवादियों को खदेड़ देती और उन्हें श्रीलंका सरकार के हवाले कर देती। भारत सरकार को चाहिए था कि वह तमिलनाडु के नेताओं को ऐसे विषय से दूर रहने को कहती जो हमारे देश के लिए जीवन-मरण का विषय बन चुका है।

माया: लेकिन तब आपके लिए इस आंदोलन को दबाना आसान हो जाता और श्रीलंका के तमिलों की वैध मांगें कुचल दी जातीं। किंतु,

क्या यही लोकतांत्रिक प्रणाली की कार्यशैली है?

जामिनी: हमारी कई खामियों के बावजूद कोई यह नहीं कह सकता कि हम अलोकतांत्रिक हैं। मुसीबतों के दौरं में भी हमारे संविधान ने विचारों, धर्म और आंदोलन की स्वतंत्रता अपने नागरिकों को प्रदान की। भले ही वह सिंहली थे अथवा तमिल या मुसलमान और हमें इस पर गर्व है।

मायाः तो आपका मतलब है कि श्रीलंका में तमिलों के दमन की जो छवि लिट्टे के नेता प्रभाकरन दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वह सही नहीं है?

जामिनी: यह प्रभाकरन कौन है? क्या आपको उसका इतिहास मालूम है? वह एक स्कूल से निकाला गया कुख्यात अपराधी था, जिसने अनेक खून किये थे—यह सब इस जातीय विवाद के उभरने से पहलें हुआ था। तो आप स्वयं ही इन लोगों की मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की रिआयत उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। उनका अस्तित्व ही हिंसा और नफरत के माहौल में फलता-फूलता है। इस समस्या को बनाये रखने में उनके कुछ निहित स्वार्थ थे। उनसे बातचीत का क्या लाभ है? इसके साथ ही हमने टी यू एल एफ जैसे तमिल राजनीतिक दलों का समस्यांओं के हल के लिए हमेशा स्वागत किया है। लेकिन आज वह भंग है। क्या आप जानते हैं क्यों? आपके तमिलनाडु के नेताओं ने तमिलों के श्रीलंका में हितों का मटियामेट किया है। उन्होंने उन उग्रवादियों को बढ़ावा दिया है जो आंतकवादियों के अलावा और कुछ नहीं हैं। मैं आज तक नहीं समझ सका कि एम॰जी॰ रामचन्द्रन ने प्रभाकरन में क्या पाया कि उसे तमिलनाडु में दामाद की हैसियत दे दी।

मायाःलिट्टे के आतंकवादी रवैये को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार का उसका राजकीय आतंकवाद से जवाब देना क्या उचित था?

जामिनी: यह किसने कहा कि श्रीलंका में राजकीय आतंकवाद था। दरअसल, तमिल आतंकवादियों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत संयमित था। वरना, जिस प्रकार के साधन हमारे पास हैं, यदि हम चाहते तो प्रभाकरन से कहीं अधिक खतरनाक बन सकते थे। तमिलों से कहीं अधिक धनवान सिंहली परिवार दुनिया के हर कोने में बसे हुए हैं, जिनसे हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। यदि हमने इस मार्ग को नहीं अपनाया, तो केवल इसलिए कि हम प्रभाकरन की अपेक्षा कहीं अधिक विवेकशील हैं।

मायाः यदि लिट्टे के नेता में विवेक की कमी है तो आपने उनसे समझौते के तहत सत्ता में साझेदारी का वायदा कैसे किया है?

जामिनी: क्योंकि हम अपने देश में शांति चाहते थे। हम प्रत्येक वर्ष एक करोड़, ३० लाख रुपए (श्रीलंका) केवल इस जातीय संकट से निपटने के लिए सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। यह खर्च हम बहुत समय तक नहीं उठा सकते। वस्तुतः शांति स्थापना के लिए हमने अधिकाधिक रिआयतें दी हैं। तमिलों की इच्छा थी कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाये, जिसे हमने माना। १९८३ में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे राष्ट्रपति जयवर्धने को टेलीफोन पर सूचित किया कि भारत को मध्यस्थता करना मंजूर है, तो हम भी तुरंत राजी हो गये। हमने सोचा कि यदि भारत स्वयं मध्यस्थता के लिए तैयार और उससे हमारे देश के एक वर्ग को प्रसन्नता होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने श्रीलंका के प्रति भारत की नीयत पर कभी शक नहीं किया।

> **भारत को यह याद रखना चाहिए कि यदि श्रीलंका में तमिलों को पृथक स्वतंत्र राज्य दे दिया गया, तो इससे तमिलनाडु में उन पृथकतावादी तत्वों को भारी शह मिलेगी, जो अभी खामोश हैं और जिनकी संख्या लाखों में है।**

मायाः क्या शांति के लिए ही आपने जुलाई समझौते के तहत तमिलों को रिआयतें दी हैं?

जामिनी: हां। हम उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों में स्थानीय सरकारों के गठन पर सहमत हुए थे, जिसमें लिट्टे के अपने नामजद प्रधान (चीफ) होने पर, उसकी प्रमुख भूमिका हुई होती। किंतु लिट्टे मुकर गया। अब वह यह अधिकार भी गंवा चुका है।

मायाः किंतु, राष्ट्रपति जयवर्धने अभी भी उन्हें माफ करने को तैयार हैं, बशर्ते वे हथियार डाल दें।

जामिनी: ऐसा विशेषाधिकार केवल राष्ट्रपति को है। जहां तक मेरा अपना विचार है, अबं लिट्टे से बात करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसकी मंशा श्रीलंका के समूचे तमिलों पर एकाधिकार जमाने की है, जिसमें तमिलों सहित कोई भी सहमत नहीं हो सकता।

मायाः क्या भारत-श्रीलंका समझौते में भीतरघात करनेवाले किसी विदेशी हाथ का आपको संदेह है?

जामिनी: फिलहाल, मैं यही कह सकता हूं कि कोई प्रमुख बाहरी ताकत समझौते के खिलाफ सक्रिय नहीं है। जो भी थोड़ा बाहरी दबाव है, वह नगण्य है।

मायाः समझौते की सफलता के लिए क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे?

जामिनी: इसमें भारत को प्रमुख भूमिका निभानी है। उसे तमिलों से हर कीमत पर हथियार डलवाने चाहिए।

मायाः क्या आप नहीं मानते कि आपका देश भारत की मौजूदा स्थिति का बेजा फायदा उठा रहा है? भारतीय सैनिक लिट्टे के हमले का निशाना बन रहे हैं। भारत कब तक यह युद्ध लड़ेगा?

जामिनी: भारत उस समय क्या कर रहा था जब हम जाफना में युद्ध कर रहे थे। क्या तब आपका देश मूक दर्शक नहीं बना था और समय-समय पर तमिलनाडु की भूमि पर आतंकवादियों को हमारे खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहा था? मैं यह नहीं कहता कि हम अब बदला ले रहे हैं। मैं सिर्फ यही संकेत करना चाहता हूं कि भारतीय एहसास करें कि हमें जाफना में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था?

मायाः भारतीय अभियान का खर्च कौन वहन कर रहा है?

जामिनी: मुझे पता नहीं। पर ऐसा विश्वास है कि भारत सरकार कर रही है।

मायाः क्या आप इसके प्रति आश्वस्त नहीं हैं?

जामिनी: नहीं। किंतु आप ऐसा पूछते ही क्यों हैं। भारत स्वेच्छा से मध्यस्थ बना है, और अब उसे परिस्थितिजन्य दायित्व तो निभाने ही होंगे। इस तथ्य से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत-श्रीलंका समझौते में भारत का कोई हित निहित नहीं था।

मायाः क्यों?

जामिनी: इसके कई जवाब दिये जा सकते हैं। पहला कि यह आपके देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसमें सेना की प्रतिष्ठा भी शामिल है। भारतीय सेना विश्व में अपनी किस्म की तीसरी सबसे बड़ी सेना होने का दावा करती है। दूसरे भारत-श्रीलंका समझौते की सफलता दोनों देशों की एकता और अखण्डता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को यह याद रखना चाहिए कि यदि श्रीलंका में तमिलों को पृथक स्वतंत्र राज्य दे दिया गया, तो इससे तमिलनाडु में उन पृथकतावादी तत्वों को भारी शह मिलेगी, जो अभी खामोश हैं और जिनकी संख्या लाखों में है। अंत में एक बात यह भी है कि भारत को इस समझौते पर अमल को सफल बनाकर यह साबित करने का अवसर मिलेगा कि भारत एक अच्छा और वफादार पड़ोसी देश है। ■

संस्थापक: स्वर्गीय श्री क्षितीन्द्रमोहन मित्र। सम्पादक: आलोक मित्र। श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा॰लि॰ के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा॰लि॰ इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

30/11/8
पुस्तकालय
कांगड़ी विश्व
हरिद्वार

डायमंड पाकेट बुक्स में

लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार

सुरेन्द्र मोहन पाठक

का 'विमल सीरीज का नया जासूसी उपन्यास

चेहरे पर चेहरा 6/-

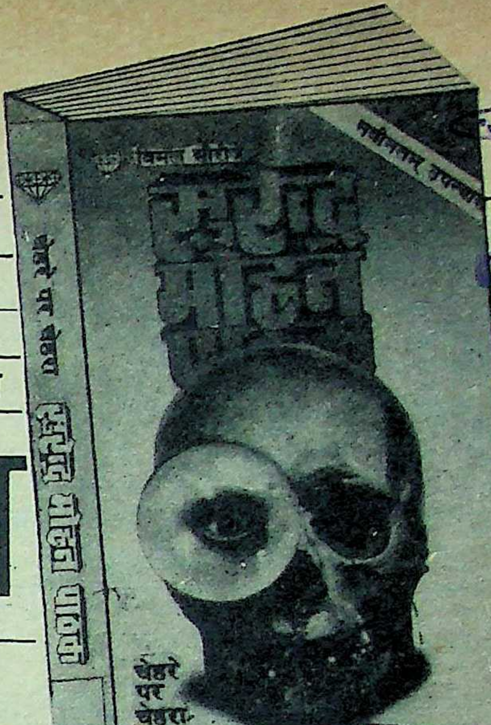
सुरेन्द्र मोहन पाठक
चेहरे पर चेहरा

कुशवाहा 'कान्त'
नीलम

प्रसिद्ध उपन्यासकार

कुशवाहा 'कान्त'

का भावनापूर्ण उपन्यास

नीलम 10/-

राज भारती का नया जासूसी उपन्यास

मौत के मुंह में 10/-

राज भारती
मौत के मुंह में

कुशवाहा 'कान्त'

का एक और भावनापूर्ण उपन्यास

चूड़ियाँ 10/-

सस्पैंस, थ्रिल इनवेस्टीगेशन के बादशाह

राहुल का नया रोमांचकारी उपन्यास

डबल रोल 6/-

लोकप्रिय युवा लेखिका

चेतना का नया भावनापूर्ण उपन्यास

वारिस 6/-

1988 में आपका भविष्य

डायमंड

राशिफल

12 राशियाँ अलग-अलग प्रत्येक 3/-

डायमंड
1988
राशिफल
SCORPIO

बेवफा की अपार सफलता के बाद

समीर का नया रोमांटिक उपन्यास

अधूरा सफ़र 6/-

Mediamind

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि. 2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

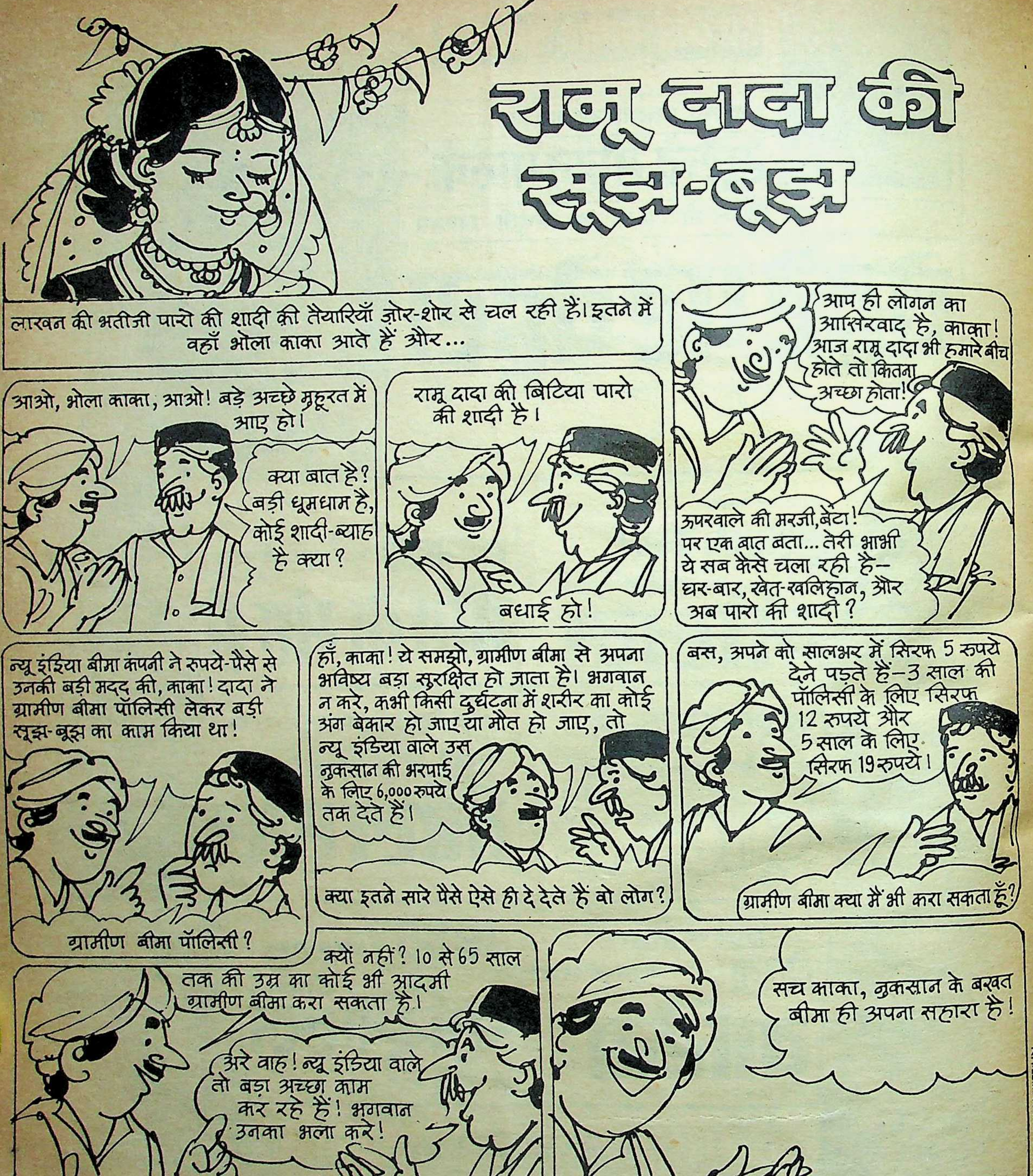
रामू दादा की सूझ-बूझ
लाखन की भतीजी पारो की शादी की तैयारियाँ ज़ोर-शोर से चल रही हैं। इतने में वहाँ भोला काका आते हैं और...
आओ, भोला काका, आओ! बड़े अच्छे मुहूरत में आए हो।
क्या बात है? बड़ी धूमधाम है, कोई शादी-ब्याह है क्या?
रामू दादा की बिटिया पारो की शादी है।
बधाई हो!
आप ही लोगन का आसिरवाद है, काका! आज रामू दादा भी हमारे बीच होते तो कितना अच्छा होता!
ऊपरवाले की मरजी, बेटा! पर एक बात बता... तेरी भाभी ये सब कैसे चला रही है- घर-बार, खेत-खलिहान, और अब पारो की शादी?
न्यू इंडिया बीमा कंपनी ने रुपये-पैसे से उनकी बड़ी मदद की, काका! दादा ने ग्रामीण बीमा पॉलिसी लेकर बड़ी सूझ-बूझ का काम किया था!
ग्रामीण बीमा पॉलिसी?
हाँ, काका! ये समझो, ग्रामीण बीमा से अपना भविष्य बड़ा सुरक्षित हो जाता है। भगवान न करे, कभी किसी दुर्घटना में शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए या मौत हो जाए, तो न्यू इंडिया वाले उस नुकसान की भरपाई के लिए 6,000 रुपये तक देते हैं।
क्या इतने सारे पैसे ऐसे ही दे देते हैं वो लोग?
बस, अपने को सालभर में सिरफ 5 रुपये देने पड़ते हैं-3 साल की पॉलिसी के लिए सिरफ 12 रुपये और 5 साल के लिए सिरफ 19 रुपये।
ग्रामीण बीमा क्या मैं भी करा सकता हूँ?
क्यों नहीं? 10 से 65 साल तक की उम्र का कोई भी आदमी ग्रामीण बीमा करा सकता है।
अरे वाह! न्यू इंडिया वाले तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं! भगवान उनका भला करे!
सच काका, नुकसान के बखत बीमा ही अपना सहारा है!
R.K.SWAMY/NIA/2977/HN

पूरी जानकारी के लिए अपने पास के न्यू इंडिया कार्यालय में पधारिए या एजेंट से मिलिए।

बीमा — नुकसान में आपका सहारा!

न्यू इंडिया एश्योरेंस

(जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की एक सहायक कंपनी)

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ५८ अंक २२

नवंबर द्वितीय पक्ष, १९८७

माया

यह अंक

आवरण कथा

माया
क्या मध्यावधि चुनाव होगा ?

यद्यपि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी मध्यावधि चुनाव कराने की योजना है, लेकिन ऐसी चर्चाएं आम हैं कि राजीव गांधी, चुनाव की अचानक घोषणा कर सकते हैं। मध्यावधि चुनाव की अफवाह किसी खास रणनीति के तहत फैलायी जा रही है, या वास्तव में इसकी योजनाएं बन रही हैं? ३०

घीसिंग

सुवास घीसिंग ने अचानक समझौते से इनकार करके १६ नवंबर को गोरखा उग्रवादियों द्वारा हथियार समर्पण का आयोजन रद्द क्यों कर दिया? ८१

उत्तर प्रदेश

प्रदेश की दो महिला राजनेता—विधायक कृष्णा रावत और इंटक की सलाहकार बोर्ड की सदस्य अनुसुइया एक दूसरे की जान लेने पर क्यों तुली हैं? ६६

राजस्थान

परिवार नियोजन के आपरेशन से श्रीमती सेठिया ऐसी किस बेबसी का शिकार हो गयीं कि वह अदालत से मौत की फरियाद कर रही हैं? ५०

नटवर लाल

ठगी के पर्याय ७३ वर्षीय नटवर लाल से 'माया' की विशेष बातचीत और उसकी आश्चर्यजनक 'ठग विद्या' के मामले: ७५

मध्य प्रदेश

युवा इंका के किन लोगों ने ऐसी स्थितियां पैदा की हैं कि आलाकमान ने अध्यक्ष को छोड़कर सारी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया? ४६

बोफोर्स: नया रहस्योद्घाटन

तोपों की दलाली के अतिरिक्त प्रति-व्यापार के जरिए ६०० करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पहुंचाने की 'तिकड़म' का रहस्योद्घाटन: २२

दिल्ली दरबार: बीन बजती रही, दरबारी झूमते रहे ६
फोटोफीचर ९
साक्षात्कार शरद जोशी: किसानों को बोतल में बंद जिन समझते हैं १४
साक्षात्कार मेनका गांधी: शायद मैं अमेठी या कहीं से न लड़ूं! १८
तथ्य-कथ्य २८
नौकरशाही: देशी अफसरों को विलायती प्रशिक्षण ४१
बिहार: शोध संस्थानों में क्या हो रहा है? ५३
बिहार: राजवंश में कलह ५७
महाराष्ट्र: अंदर ही अंदर सुलग रहा है 'विदर्भ' ६०
उत्तर प्रदेश: देहरादून-मसूरी विकास योजना पर विवाद ६८
घर का भेदी: बात अपने तक ही रखियेगा ७२
घटना: तमिलनाडु में राजनीतिक उबाल ८६
अर्थतंत्र: अभी तो महंगाई और बढ़ेगी ८९
अर्थतंत्र: योजना आयोग: एक मरणासन्न संस्था ९१
परदे के पीछे ९४
चिकित्सा: अब गुब्बारे करेंगे दिल का इलाज ९७

© इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी
सीनियर विजुअलाइजर
शांतनु मुखर्जी
सज्जा
आर०एन० सिन्हा

० प्रधान कार्यालय: २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ६१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७६३ टेलेक्स: ०३१,६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

माया
हिन्दू उग्रवाद का शंखनाद

भारतीय नेताओं ने भांग खा ली है?

'माया' (३० अक्तूबर) में प्रकाशित सुब्रह्मण्यम स्वामी का अभिमत 'भारत में श्रीलंका का विलय ही अब एकमात्र रास्ता है' पढ़ा, जो भारत के वर्षों से अन्तर्निहित विस्तारवादी दृष्टिकोण को उजागर करता है। जिस तरह जिन तर्कों के आधार पर उन्होंने श्रीलंका के भारत में विलय को उचित ठहराया, उसी तरह मैं भी यह कह सकता हूं कि सन् १७५७ में पलासी के युद्ध के बाद कंपनी सरकार ने छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी, तो किसी भारतीय का यह हक कैसे हो सकता है कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किये गये संपूर्ण भौगोलिक साम्राज्य को वर्तमान भारत का ही एक अंग माने जो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त ही आजाद हो गया था। वस्तुतः प्रत्येक भारतीय को यह मानना चाहिए कि आज वे जिस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, वह अंग्रेजों की देन है। फिर भी आज के भारतीय राजनेताओं द्वारा व्यक्त की जा रही इस तरह की विचारधारा संकीर्ण एवं घोर निंदनीय ही नहीं दक्षिण एशिया के छोटे-छोटे राज्यों की स्वतंत्रता और सार्वभौम सत्ता पर सीधा हस्तक्षेप है। **—श्याम कुमार**, जनकपुरधाम, नेपाल

क्या टिकैत सचमुच चमत्कारी नेता हैं?

भारत के राष्ट्रीय क्षितिज पर महेंद्र सिह टिकैत का उदय (आवरण कथा, अक्तूबर द्वितीय पक्ष) एक अनोखी घटना है। इसे इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि टिकैत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कतई नहीं है और वह एक समान स्वर में सत्तापक्ष व विपक्ष सबकी निंदा करते हैं। चूंकि किसानों के हितों का दावा करने के नाम पर हर पार्टी ने अपना हित ही साधा है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि टिकैत किसानों के हितों के लिए सच्चे अर्थों में काम करने वाले नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस लेने को मजबूर करके उन्होंने अपनी सफलता के झण्डे गाड़ दिये हैं। **—बृज राज किशोर**, १२६-ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून

'माया' अक्तूबर अंक (द्वितीय पक्ष) पढ़ा। उससे महेंद्र सिंह टिकैत की मानसिकता का पता चला कि वह बहुत ही कमजोर एवं अदूरदर्शी हैं। उनके पास कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। वह केवल जाति के आधार पर जाटों की राजनीति कर रहे हैं और मुझे तो यह लगता है कि उनका यदि यही रवैया रहा तो धीरे-धीरे वहां भी उग्रवाद पनपेगा। उनके कार्यक्रमों से किसानों का थोड़ा-सा भी लाभ होने की उम्मीद नहीं है। उनके द्वारा चलाये जा रहे आंदोलनों से अल्पकालीन लाभ भले ही हो जाये। **—राजेंद्र राठी**, मेन रोड, हिंगनघाट

'माया' के अक्तूबर द्वितीय पक्ष का विस्तृत रूप से अवलोकन किया। मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया—महेंद्र सिंह टिकैत ने। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में इन्हें इतना सशक्त जनसमर्थन प्राप्त है, बड़े प्रसन्नता की बात है। इन्हें गरीबों तथा किसानों का 'मसीहा' भी कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। बस, एक ही शंका है कि अभी तो ये अराजनीतिक हैं किंतु यदि भविष्य में ये राजनीतिक जीवन में उतरे तो क्या उस समय भी इनको इतना ही जन-समर्थन प्राप्त होगा? या उस समय भी ये आज की तरह से अपने नियमों तथा सिद्धांतों पर अडिग रह सकेंगे? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन्हें दूषित राजनीति से बचायें। **—सुधीर खरे 'कमल'**, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोरबा, प्रगति नगर, म०प्र०

'माया' अपनी निष्पक्षता बनाये रखे

अक्तूबर महीने का दूसरा अंक पढ़ा। 'सत्तारूढ़ दल में हड़कंप' पढ़कर ऐसा लगा मानो 'माया' अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता भूलती जा रही है। मैं 'माया' का पुराना पाठक हूं पर अचानक वी०पी० सिंह के कांग्रेस त्यागने के बाद जिस प्रकार 'माया' उनकी भक्त हो गयी है, वह निष्पक्ष पाक्षिक के लिए उचित नहीं है। विद्याचरण शुक्ल जैसे बदनाम व्यक्तित्व को आपने जिस तरह 'हीरो' बनाने की कोशिश की है, वह बिलकुल ही ठीक नहीं है। वी०पी० सिंह अपने 'जनमोर्चा' को गैर राजनीतिक कह रहे हैं, पर अपने सहयोगी एम०पी० को उन्होंने त्याग-पत्र देने की सलाह नहीं दी और खुद भी राजीव के नाम पर

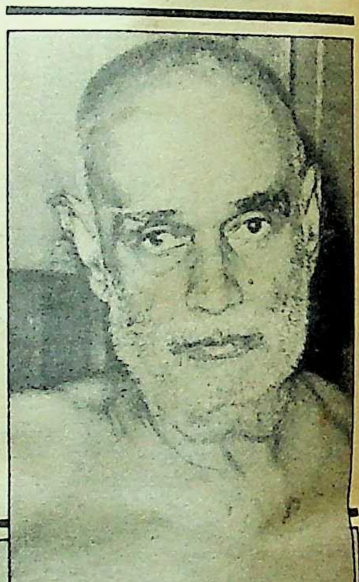

भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे

'माया' (अक्तूबर द्वितीय पक्ष) में 'लोग' के अंतर्गत निरंजन देव तीर्थ के सती विषयक विचार पढ़कर महा कष्ट हुआ। हृदय यह सोचने पर विवश हो गया कि बड़ा पद प्राप्त कर लेने से ही कोई व्यक्ति सत्य के दर्शन नहीं कर लेता। क्या सरस्वतीजी वैदिक काल या रामायण काल की कुछ ऐसी सतियों के नाम गिनवा सकते हैं, जिन्होंने मृतक पति के साथ आत्मदाह किया हो। यदि सरस्वतीजी की कसौटी पर परखा जाये तब तो महाराज दशरथ की रानियां शायद साधारण पतिव्रताओं की भी कोटि में न आयेंगी।

जिस मुगल काल का उदाहरण सरस्वतीजी ने दिया है उस समय स्त्रियां पति-प्रेम के कारण नहीं, बल्कि मुसलमानों द्वारा अपने को अपमानित होने से बचाने के लिए आत्मदाह करती थीं और वही प्रथा लगातार चलती रही, फलस्वरूप कालांतर में वह धार्मिक कृत्य कहलाने लगी। यह तो धर्म नहीं, अपधर्म था। महाभारत में केवल माद्री ने मृत पाण्डु के साथ आत्मदाह किया था, किंतु माद्री की स्थिति इतनी कारुणिक थी कि उनके द्वारा उस मनोदशा में लिये गये निर्णय में हम उचित या अनुचित की आशा नहीं रख सकते।

यदि मृत-पति के साथ आत्मदाह इतना ही पुनीत होता, तो अवश्य ही राम या कृष्ण जोकि हिंदू समाज की रीढ़ हैं, ने इस प्रथा का कहीं उल्लेख या समर्थन किया होता। रामचरितमानस, बाल्मीकीय रामायण तथा श्रीमद्भागवत में भी कहीं आत्मदाह करने वाली स्त्रियों का गुणगान हमें नहीं मिलता।

यदि सरस्वतीजी माद्री के चरित्र को आदर्श मानकर इस प्रथा के समर्थक हैं, तब तो उन्हें द्रौपदी के आदर्श के अनुसार बहुपति और सरस्वती के चरित्र के आधार पर संन्यासियों द्वारा कुमारियों के सन्तानोत्पत्ति आदि को भी समर्थन देना पड़ेगा।

मेरी सरस्वतीजी से प्रार्थना है कि वह अपने धर्मगुरु पद को बहुसंख्यक हिंदुओं की दृष्टि में कलंकित न करें। जिस तरह दिग्भ्रमित व्यक्ति को रास्ता बताना पाप नहीं है, उसी तरह पति की मृत्यु से उत्पन्न भविष्य की असुरक्षा से व्याकुल स्त्री को आत्मदाह से रोकना भी पाप नहीं है, क्योंकि उस समय वह विवेकहीन होती है। अपने ज्ञान का जितना दुरुपयोग सरस्वतीजी सती प्रथा का समर्थन करने में कर रहे हैं यदि उसका आधा भी विधवा-विवाह के समर्थन, दहेज-प्रथा-उन्मूलन आदि सामाजिक बुराइयों को हटाने में सदुपयोग करते, तो हिंदू सदियों तक उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते। यदि वह यह नहीं कर सकते तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया चुप रहें और हिंदुओं को बर्बर बनने के लिए प्रेरित न करें। हमें अपना मार्ग स्वयं ढूंढ़ने दें। इस संदर्भ में मैं स्वामी अग्निवेश की चुनौती की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। **—अखिलेश कुमार पाठक**, बागडोगरा, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

चिट्ठियां

मिली अपनी संसद-सदस्यता को खोने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन लोगों में जरा भी नैतिकता होती, तो पार्टी से हटने के तत्काल बाद ये लोग संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते। संसद की सीट उन्हें एक कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से इंदिराजी एवं राजीव गांधी की तस्वीर की बदौलत मिली है।

वी०पी० सिंह भी जब तक मंत्री-पद हथियाकर बैठे थे तब तक उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता था और आज पार्टी से निकाल देने के बाद सारी बुराई की जड़ राजीव गांधी और भ्रष्टाचार का मूल कांग्रेस हो गयी है। अतः वी०पी० की चाटुकारिता के बजाय उनकी सही मानसिकता को जनता के सामने प्रकट करें। **—वीरेन्द्र शर्मा,** घुसुड़ी, हावड़ा, प० बगाल

सराहनीय लेकिन त्रुटिपूर्ण

'**मा**या' के अक्तूबर द्वितीय पक्ष, १९८७ में स्व० किशोर कुमार का फोटोफीचर एवं लेख पढ़ा। इस श्रद्धांजलि के लिए धन्यवाद। आपके इस प्रयास की सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता। लेकिन आपकी पत्रिका में स्व० किशोर कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म 'पड़ोसन' (जो उनकी सफलतम फिल्म थी) का कोई उल्लेख नहीं है। यह त्रुटि असहनीय है। **—जगदीश स्वरूप बिसारिया,** परमेश्वर निवास, प्रकाश नगर, कैनाल रोड, रायबरेली

अक्तूबर द्वितीय पक्ष को 'माया' में किशोर कुमार के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा। आज हमारे बीच से पार्श्वगायन की दुनिया से तीसरा गायक भी चला गया। अब शायद ही इस 'आल राउंडर' गायक की जगह कोई ले पाये। किशोर कुमार नें हमारे लिए हजारों गीत गाये, उन्होंने किसी गीत में जीने की राह दिखायी, किसी में हंसाया, किसी में रुलाया और किसी में दिल को गुदगुदाया है। **—रसिक बिहारी बसेड़िया,** मु० पुरैना (रंधीर) पो०—जमनिया, होशंगाबाद, म०प्र०

लंका में सब बावन गज के हैं

'**मा**या' (अक्तूबर द्वितीय पक्ष) में प्रकाशित रिपोर्ट 'विलासिता-पूर्ण विमान क्यों खरीदे गये?' पढ़ी। बोफोर्स तोपों की खरीद और उसके विवादास्पद होने के बाद उपयोगिता, जांच-परख और खर्चों का मूल्यांकन किये बिना २०-२० करोड़ रुपए मूल्य के दो गल्फस्ट्रीम-३ विमानों की खरीदी शंकास्पद है। विमानों की खरीद के संबंध में एवियेशन रिसर्च सेंटर और राजीव गांधी के परस्पर विरोधी बयानों ने शंका की कड़ी को और मजबूत कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी सरकारी को तर्क और बुद्धि से कोई सरोकार ही न हो। भारत की गरीब जनता वर्तमान समय में भयंकरतम सूखे से जूझ रही है एवं उसे सरकार की सहायता की आवश्यकता है, लेकिन बहुमत प्राप्ति से मदांध राजीव गांधी, जनता की भावनाओं को आहत कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस खरीद की जांच की मांग किससे की जाये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लंका में सब बावन गज के हैं। **—संजय चतुर्वेदी,** पातरा परी घाट, भोपाल, म०प्र०

राजीव चला जायेगा, तो जैसे रांड़ हो जायेगा देश !

'**मा**या' (अक्तूबर द्वितीय पक्ष) में छपा साक्षात्कार 'राजीव चला जायेगा, तो जैसे रांड़ हो जायेगा देश !' पढ़ा। साक्षात्कार पढ़ने से यह बात साफ जाहिर होती है कि बहुगुणाजी अभी भी राजीव-अमिताभ तथा अन्य युवा वृंदों से डरे हुए हैं। पं० नेहरू ने अपनी किताब (विश्व इतिहास की झलक) में लिखा है कि औरंगजेब की सेना से मार खाकर अंग्रेज इतना डर गये कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य भहरा गया, फिर भी अंग्रेजों ने बहुत दिनों तक सैनिक हस्तक्षेप और दखलंदाजी करना उचित नहीं समझा। ठीक ऐसा ही बहुगुणाजी के साथ लगता है, जबकि राजीव-चमत्कार का युग समाप्त हो चुका है।

पहले भी राजीव चमत्कार प्रभावी नहीं होता, लेकिन आम जनों के सामने दूसरा कोई था ही नंहीं। और इंदिरा गांधी को गोली मारी गयी थी। इसलिए राजीव स्वाभाविक रूप से 'वरमाला' के हकदार हो गये। सत्ता रूपी सुंदरी का दामन थामने को उन्हें बस यों ही मिल गया। अगर अगला चुनाव भी राजीव जीत जाते हैं, तभी यह माना जायेगा कि यह 'शादी' जीवनपर्यंत चलेगी। **—अशीश कुमार चौधरी,** बलभद्रपुर, लहेरिया सराय, दरभंगा, बिहार

खयालात

गुरुचरण सिंह तोहड़ा पंजाब में हो रही राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के सूत्रधार हैं।

—बूटा सिंह, संसद में दिये बयान से

भारत ने तमिल आतंकवादियों को हथियार देने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि हथियार दिये भी। हम नहीं जानते कि केंद्र सरकार ने दिये या तमिलनाडु सरकार ने। हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं।

—लंका के राष्ट्रपति जयवर्धने, 'न्यूयार्क टाइम्स' में

हमने कोई ऐसी कसम नहीं खा रखी है कि हम राजनीति में नहीं आयेंगे। इस बात की संभावना है कि निकट भविष्य में आर०एस०एस० भी राजनीति में आ सकता है।

—बाला साहब देवरस, 'एन०आई०पी०' में

हम देश को उन धूर्तों और बदमाशों के हाथ में नहीं जाने देंगे, जो तथाकथित राष्ट्रीय नेता बन गये हैं।

—युवा कांग्रेस के नये अध्यक्ष गुरुदास कामत, 'रविवार' में

कितने शंकराचार्य तो हिंदू धर्म के मूल तत्वों तक को नहीं समझते।

—चंद्रशेखर 'टेलीग्राफ' में

पाक में जनरलों का ही लोकतंत्र है।

—बेनजीर भुट्टो 'रांची एक्सप्रेस' में

सिर्फ पदयात्रा करके किसी सांसद को मंत्री-पद मिलता, तो हर नेता सबसे पहले पदयात्रा ही करता।

—सुनीलदत्त, 'अवकाश' में

सैयद शहाबुद्दीन जैसे कठमुल्ला लोग इस्लाम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।

—भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, 'दैनिक जागरण' में

यदि जनमोर्चा ने मुझे कहा तो मैं अमिताभ बच्चन के विरुद्ध चुनाव अभियान में अवश्य हिस्सा लूंगा।

—राजबब्बर

स्त्री का गौरव एक सरकार की जिंदगी से कहीं ज्यादा महान है।

—बालकवि बैरागी, 'हिंदुस्तान टाइम्स' में

सिनेमा के लोग यदि उन्हें (दर्शकों को) अपने 'कार्यकर्ता' समझने लगें, तो वे बेवकूफों की जन्नत में रह रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात और है, लेकिन यदि बब्बर (राज) समझते हैं कि उनके हुक्केबरदार होकर वह भी नेता हो गये, तो मामला कारुणिक है।

—'नवभारत टाइम्स' की एक संपादकीय से

मेरे लिए देश पहले है, कप्तानी नहीं।

—कपिल देव, गोवा के एक दैनिक 'नवहिंद टाइम्स' में

मैं राज्यसभा की सदस्यता तक स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा अभी क्रिकेट की सेवा करने की है।

—सुनील गावस्कर, 'टाइम्स आफ इंडिया' में

आज के अभिनय की अंधी दौड़ से मैं थोड़ा-सा अलग हूं। **—दिलीप कुमार, 'धर्मयुग' में**

जेल से जमानत पर छूटने के बाद मैं फिर अपने धंधे में लग जाऊंगा।

—कुख्यात ठग नटवरलाल, 'चौथी दुनिया' में

बूटा सिंह

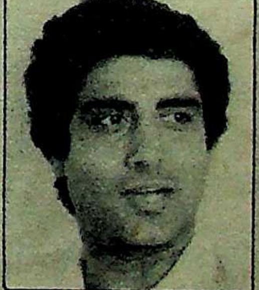

राज बब्बर

नटवर लाल

बीन बजती रही, दरबारी झूमते रहे

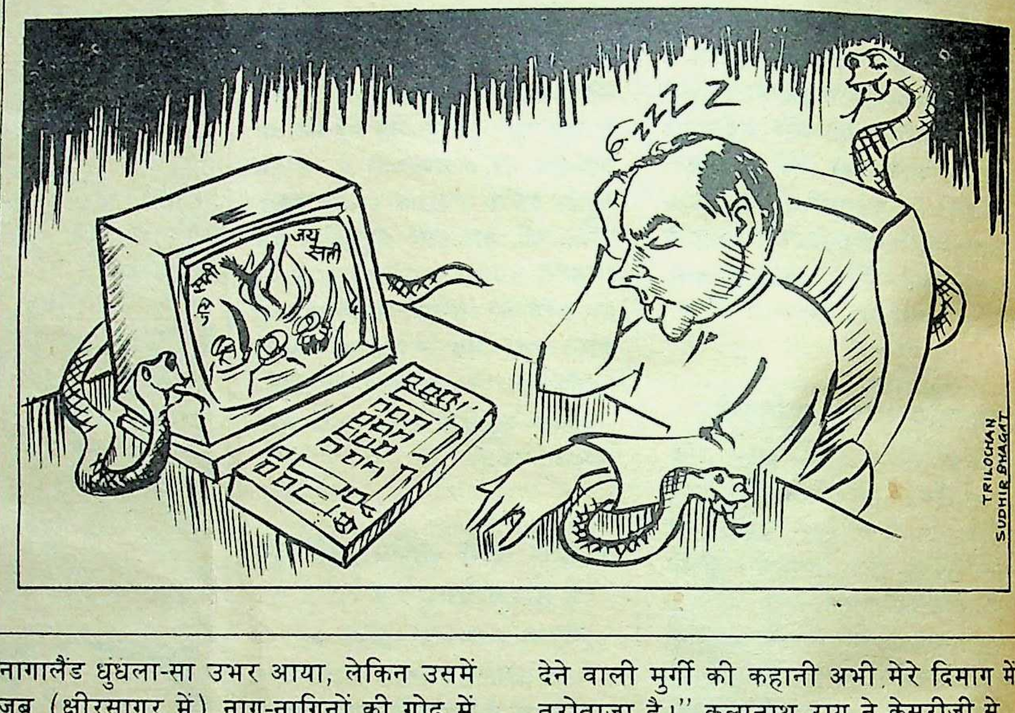

तेरह नवंबर की रात को जब दिल्ली दरबार नागालैंडी चुनावी युद्ध में नीमहोशी के आलम में 'एयरलिफ्ट' करके दरबार में गिराये गये, तो हर तरफ कोहराम मच गया। दिल्ली दरबार के वी०आई०पी० एरिया में 'रेड एलर्ट' का सायरन घू...घू...करके बजने लगा। 'काम्पोज' की गोलियों से सुलाये गये दरबारियों के कम्बल तुरन्त खींच लिये गये—"दिल्ली दरबार के ऊपर मदहोशी छा रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो।" दरबारियों को तुरन्त मैथेड्रिन की गोलियां निगलवायी गयीं। दवा के अंदर जाते ही, दरबारी काले लंगूरों की तरह उछलने लगे। हाका देकर सारे दरबारियों को दरबार में लाया गया। कुछ दरबारी कच्छा-बनियान, कुछ लुंगी तथा कुछ दरबारी मिनिस्ट्री की 'ओथ' के चक्कर में अभी तक टीनोपाली कुरते-धोती में कफनियाये सोते रहे, वैसे-के-वैसे दिल्ली दरबार में आ गिरे।

दिल्ली दरबार को सेम पित्रोदा 'मानिटर स्क्रीन' पर यह दिखाने में लगे हुए थे कि रूपकंवर के सती होने के बावजूद पूरा राजस्थान अभी भी उनके साथ परचम तले पूरी तरह महफूज है। हरिदेव जोशी 'हर-हर महादेव' की जय-घोषणा के साथ अपने एक ही हाथ से पूरे राजस्थान को सती बनाने के लिए जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में दादा पाटील शरद पवार को अपने कंधे पर उठाये अपनी ७०वीं वर्षगांठ पर ताल ठोंक रहे हैं। नागपुर में विधानसभा की गुम्बज पर चढ़े मुख्यमंत्री शंकर राव चह्वाण 'ह्विप' की रस्सी का फंदा सांगली की ओर भाग रहे विधायकों के गले में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेशी वीर बनाम बहादुर बनाम सिंह राजा मांडा की तरफ निहार रहे विधायकों को चमचमाती कारों का रंगीन फोटो दिखाकर यह कहते दिखायी पड़ रहे हैं—"यह कार पसंद नहीं, तो यह कार ले लो। कार से नफरत है, तो मकान ही ले लो, लेकिन ललचाई नजरों से राजा मांडा की तरफ मत देखो।" मध्य प्रदेशी मोतीलाल बोरा को अर्जुन सिंह खाली चीनी के बोरे में बंद करने के लिए हाथापाई पर उतारू हैं, तो नरेश चन्द्र चतुर्वेदी बीच-बचाव करते हुए दिखायी पड़ रहे हैं। लेकिन बार-बार बटन दबाने और चैनल बदलने के बावजूद 'मानिटर स्क्रीन' पर नागालैंड नहीं आ पा रहा है। सेम को पीछे धकिया कर सतीश शर्मा ने बटन दबाना शुरू किया और बड़बड़ाने लगे—"यह क्या हो रहा है? हमारे इंका स्क्रीन पर यह नागालैंड क्यों नहीं आ रहा है! दिल्ली दरबार तो नाग-नागिनों को यह कह कर आये थे कि ६० की विधानसभा में हमको जिताओगे, तो हम उपहार में तुम्हें विधान परिषद भी देंगे। उसमें तुम लोग बिना चुनाव लड़े गुलछर्रे उड़ा सकते हो।" जब सतीश शर्मा ने काफी कप्तानी दिखायी. तो स्क्रीन पर कुछ सैकिंडों के लिए नागालैंड धुंधला-सा उभर आया, लेकिन उसमें जब (क्षीरसागर में) नाग-नागिनों की गोद में आंध्राई एन०टी० रामाराव विष्णु बने दिखायी पड़े, तो दरबार में कोहराम मच गया—"यह नचनिया नागालैंड में क्या कर रहा है!" सतीश शर्मा की सारी कप्तानी हवलदारी में जब बदलती नजर आने लगी, तो उन्होंने तुरन्त चैनल बदल दिया। मानिटर की पूरी स्क्रीन पर सफेदी आ गयी। पीछे पट्टेदार कच्छे-बनियान में खड़े सीता राम केसरी ने भांगड़ाई लुंगी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बुदबुदाते बूटा सिंह से कहा, "बूटे, दिल्ली मदहोशी में डूब रहा है। यह कप्तान मानिटर स्क्रीन पर नागालैंड नहीं ला पायेगा। हम लोगों को कोई और उपाय दिल्ली दरबार को इस खुमारी से निकालने के लिए करना होगा, नहीं तो लेने-के-देने पड़ सकते हैं।" बूटा सिंह ने ग्रंथ साहिब का पाठ तेज कर दिया। पीछे से तिफंगे अंडरबियर में धकियाते हुए कल्पना में डूबते-उतराते कल्पनाथ राय ने केसरीजी के कंधे पर हाथ रख दिया—"दिल्ली दरबार की खुमारी जाये, उसके पहले इन्हें लादकर राष्ट्रपति भवन ले चला जाये। तुम तो राज्यसभा के मैम्बर हो नहीं, पर मैं हूं। मेरी 'ओथ' हो जायें। उसके बाद दिल्ली दरबार भाड़ में जायें या राजा मांडा, हम लोगों को क्या लेना देना।" केसरीजी ने राय का हाथ कंधे से उतार दिया—"कल्पनाथ राय बकवास बंद करो। तुम भूल गये, लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी अभी मेरे दिमाग में तरोताजा है।" कल्पनाथ राय ने केसरीजी से तुनक कर कहा—"धकियाते क्यों हो, तुम 'ओथ' ले लो। लेकिन छह महीनों में चुनकर कहां से आओगे! चलो दिल्ली दरबार को उठाकर राष्ट्रपति भवन ले चला जाये। मंत्री बनना हमारा धर्म ही नहीं, कर्तव्य भी है। आने वाली पीढ़ी हमको धिक्कारेगी कि हम लोगों ने मंत्री बनने में कोई रुचि नहीं ली...।" राय केसरीजी का हाथ पकड़कर खींचने लगे, लेकिन उसी समय पीछे से कैंची सिगरेट का गुल झाड़ते हुए, फटफटाते हुए फोतेदारजी आ गये—"केसरीजी यह क्या खींचातानी हो रही है। कभी तो सीरियस रहा करिये।" कल्पनाथ राय ने केसरीजी का हाथ छोड़ दिया। फोतेदारजी के पीछे सरकारी अस्पताल सिर पर उठाये पी०वी० नरसिम्हा राव और उनके पीछे नर्स के लिबास में सरोज खापर्डे दनदनाती दरबारियों की भीड़ को तितर-बितर करती हुई आ गयीं। हर तरफ शोर होने लगा—"पीछे हटो, पीछे हटो...।"

डाक्टरों की टीम दिल्ली दरबार के आला फिट करे कि उसके पहले सरोज खापर्डे ने दिल्ली दरबार की छाती बुलेटप्रूफ जैकेट को चीर कर अपने कान मयथोबड़े के छाती में फिट कर दिये। डाक्टरों को जब आला फिट करने के लिए छाती का कोई हिस्सा न मिला, तो उन्होंने नरसिम्हा राव की तरफ इशारा

किया कि 'इन मोहतरमा को तो हटाया जाये।' पी०वी० ने पीछे से सरोज का जूड़ा पकड़कर खींचा, तो उनके हाथ में नकली बालों का गुच्छा आ गया। पी०वी० नाराज होकर बड़बड़ाये—"दिल्ली दरबार में हर तरफ नकली माल की भरमार है। कब तक इस डुप्लीकेट माल से दिल्ली दरबार चलेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं...।" पीछे से बूटा सिंह ने आकर पी०वी० के टकले सिर पर हाथ फेरा—"गुस्सा मत करो पी०वी०। २१वीं सदी में जाने के लिए पैर लटकाये बैठे हो और यह असली-नकली का सवाल उठा रहे हो। असली-नकली यह सब मन का भ्रम है। कमर में हाथ लगाओ और खींच लो।" पी०वी० अनमने खड़े रहे, तो बूटा सिंह ने प्रश्न किया—"अब तुम्हारे मन में यह शंका हो रही होगी कि अगर कमर भी नकली निकल गयी, तो क्या होगा ? शंका उचित है। लेकिन प्रयास तो करना ही होगा। अब हम लोग पंजाब के आतंकवाद से निपट नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं। तुम नयी शिक्षा नीति लागू नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके लिए प्रयास तो कर रहे हो। दिल्ली दरबार बोफोर्स से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं। हे पी०वी०, तुम प्रयास करो, सफलता-असफलता देने वाला तो वाहे गुरु है!" बूटा सिंह का दर्शन सुनकर पी०वी० ने गीता का 'कर्मणे वाधिकारस्ते...।" वाला श्लोक विशुद्ध संस्कृत में उच्चारित किया। पी०वी० कर्म के लिए आगे बढ़ें कि उनके पहले पीठ में खुजली होने के कारण सरोज दिल्ली दरबार से अलग हो लीं। पी०वी० की सांस में सांस आयी और उन्होंने सरोज को उनके नकली बालों का घोंसला पकड़ा दिया। सरोज पी०वी० पर आपे से बाहर हों, उसके पहले दिल्ली दरबार पर डाक्टरों की टीम टूट पड़ी। पी०वी० सरोज से उलझने की जगह दिल्ली दरबार की तरफ ताक-झांक करने लगे।

दिल्ली दरबार की खुमारी बढ़ने लगी तो दरबारियों ने तुरन्त 'चिन्ता' का मेकअप अपने थोबड़े पर मलना शुरू कर दिया। उसी समय रिपोर्ट आ गयी। दरबार में उद्घोषणा हुई कि पिछले दिनों जब दिल्ली दरबार नागालैंड के चुनावी युद्ध में शरीक होने के लिए गये थे, तो वहां नाग-नागिनों ने बहुत डंसा। इसीलिए दिल्ली दरबार को खुमारी चढ़ी हुई है। उद्घोषणा के बाद दिल्ली दरबार में कोहराम टेप बज उठा।

बघेल ठाकुर अर्जुन सिंह टेलीफोन के खम्बे पर चढ़े अपनी भोपाल की लाइन ठीक कर रहे थे। वह उतर कर दिल्ली दरबार की ओर भागें। मोतीलाल बोरा पहले से ही वहां मौजूद थे। कहीं फिर अर्जुन सिंह हमला न बोल दें, इसलिए नरेश चन्द्र चतुर्वेदी उनका विमान पालम पर उतरे कि उसके पहले ही वह छलांग लगाकर, किसी को इंकाई मार्क्सवाद पर प्रवचन दे रहे केदारनाथ सिंह की खोपड़ी पर आ गिरे। केदार ने सुल्तानपुरिये लहजे में कहा—"वीर बहादुर खोपड़ी पर ऊपर से कूद लो, मुझे कोई प्रेशानी नहीं लेकिन खोपड़ी पर चढ़कर कूदोगे, तो फिर मुश्किल होगी।" वीर बहादुर के०एन० को विशुद्ध अंग्रेजी में 'इगनोर' करके आगे बढ लिए। दादा पाटील, शरद पवार को अपने कंधे पर लादे हुए धोती की गांठ खोले हुए दनदनाते हुए दिल्ली दरबार में घुस गये। डाइबिटीज का रोग मुद्दत्त से पाले हुए हैं, लेकिन हाथ में महाराष्ट्र की शूगर लाबी वह हमेशा लिए रहते हैं। चीनी का मुट्ठा फांक, दादा पाटील जैसे ही शंकर राव चह्वाण पर लपके, गुलाम नबी आजाद बीच में आ गये। दादा ने गुलाम को धकियाते हुए कहा—"अबे नबी गुलाम तू इस घाटी को कब तक बचायेगा। अब मैं नहीं, मेरा किसान संगठन ही इसकी ऐसी-तैसी कर देगा। मुझे तो अब दिल्ली दरबार से दो-टूक बात करनी है। राजस्थानी पगड़ी छोड़ कर अब मैंने फिर से अपनी मराठा पगड़ी सिर पर पहन ली है।" दादा का ब्लड प्रेशर मुंह को आये कि उसके पहले कंधे पर सवार पवार ने दादा को रोक लिया। बिहार के बिंदेश्वरी दुबे कम्बल ओढ़े मुर्गे की टांग नोंच रहे थे कि किसी ने पीछे से उनको धकिया दिया। औंधे मुंह गिरने से संभलते हुए दुबेजी चिल्लाये—"यह जगन्नाथ मिश्र अब मेरे लिए प्रेत हो गया है। न खाने देता है, न सोने देता है। अब हवा बनकर आया और मुझे धकिया कर चला गया।"

दिल्ली दरबार में जब कोहराम का टेप अपने वाल्यूम पर बजने लगा, तो दरबारियों के स्वर मंद पड़ गये। पट्टेदार कच्छा-बनियान में केसरीजी जार्ज से कुछ हाथ हिला-हिलाकर बतियाते नजर आये। गोपी अरोड़ा भी उसमें शामिल हुए, लेकिन बाद में मुंह बिचका कर अलग हो लिये। प्रोफेसर रंगा की समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है? वह जिससे पूछते वह अगले पर टाल देता। किसी ने उनसे कह दिया कि अभी तक आपने सोशलिस्ट फोरम की कोई काट नहीं पैदा की, इसीलिए यह सब हो रहा है। लेकिन किसी ने मूल बात नहीं बतायी। केसरीजी के गोल में नरेश चन्द्र चतुर्वेदी शामिल होकर कविता में अपने सुझाव देने लगे। केसरीजी तभी तेजी के साथ बाहर की ओर लपके। कुछ ही देर में वह 'स्लो मूवी' की स्टाइल में अवतरित हुए। उनके पीछे सपेरे बीन पर फिल्म नागिन की धुन—"तेरा मन डोले...।" बजाते हुए आ रहे थे। सारा दरबार खुशी से झूम उठा।

हरिदेव जोशी 'हर हर महादेव' की जय-घोषणा के साथ अपने एक ही हाथ से पूरे राजस्थान को सती बनाने के लिए जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में दादा पाटील शरद पवार को अपने कंधे पर उठाये अपनी ७०वीं वर्षगांठ पर ताल ठोंक रहे हैं। नागपुर में विधानसभा की गुंबज पर चढ़े मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण 'ह्विप' की रस्सी का फंदा सांगली की ओर भाग रहे विधायकों के गले में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेशी वीर बनाम बहादुर बनाम सिंह, राजा मांडा की तरफ निहार रहे विधायकों को चमचमाती कारों का रंगीन फोटो दिखाकर यह कहते दिखायी पड़ रहे हैं—"यह कार पसंद नहीं, तो यह कार ले लो। कार से नफरत है, तो मकान ही ले लो, लेकिन ललचाई नजरों से राजा मांडा की तरफ मत देखो।"

पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया गया कि नागालैंड से दिल्ली दरबार को आने वाले सभी सड़क और हवाई मार्ग खाली कर दिये जायें, क्योंकि सपेरों की बीन बजना शुरू हो गयी है। नागालैंड के जिन नाग-नागिनों ने दिल्ली दरबार को डंसा है वे अपना विष वापस पीने आयेंगे। टाइटलर और पायलट के साथ आस्कर फर्नांडीज को हवाई और सड़क मार्ग की चौकसी की जिम्मेदारी सौंपी गयी। दिल्ली दरबार में फिर यानी १८ दिन तक जमकर सपेरों की बीन बजी, लेकिन नागालैंड से न तो नाग और न ही कोई नागिन दिल्ली दरबार की ओर आयी।

छह दिन दिल्ली दरबार में बीन बजती रही और दरबारी झूमते रहे। वेंकटरमण अपने राष्ट्रपति भवन के गुम्बज पर चढ़कर सारा नजारा देखते रहे। उनको दूसरे हक्कारों से भी सूचनाएं मिलती रहीं। अंत में वेंकटरमण ने दिल्ली दरबार में पुछवाया कि सपेरों की बीन पर सांप आकर तो झूम नहीं रहे हैं, ये दरबारी इतना क्यों झूम रहे हैं? इनकी शक्लें भी सांपों जैसी हो रही हैं।

जैसे ही दिल्ली दरबार के खास कारिंदों को वेंकटरमण का निर्देश प्राप्त हुआ कि यह पता लगाया जाये कि सपेरों की बीन पर ये दरबारी पिछले छह दिनों से इतना मदमस्त होकर क्यों झूम रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? दरबार के खास और अदृश्य कारिंदों ने सपेरों की बजती हुई बीन के बीच पंचम में उद्घोषणा करायी कि "सपेरों की बीन पर तो सांपों को झूमना चाहिए। आप दरबारी क्यों झूम रहे हैं?" इस उद्घोषणा के जवाब में सारे दरबारियों का झूमते हुए समवेत स्वर में जवाब था—"हम लोग आस्तीन के सांप हैं। इसीलिए सपेरों की बीन पर पिछले छह दिनों से झूम-रहे हैं।" इस जवाब के बाद दिल्ली दरबार में सन्नाटा छा गया।

—दरबारी लाल

जनमोर्चा की नयी प्रेरणा

जनमोर्चा के नेता इस बात को लेकर काफी परेशान हो उठे हैं कि पूर्व रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह की सभाओं में अब उतनी भीड़ नहीं हो पा रही है, जितनी उनके पहले दौरों में होती थी। पिछले दिनों इस विषय को लेकर अरुण नेहरू के निवास स्थान पर एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें वी०पी० सिंह के अलावा रामधन, संयोजक जनमोर्चा, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इस गुप्त बैठक में वी०पी० सिंह ने यह स्वीकार किया कि उनके पास कहने के लिए कुछ सनसनीखेज नहीं है, इसलिए दुबारा जनता उनकी सभाओं में उतने उत्साह के साथ नहीं आ रही है, जितनी पहले आती थी। रामधन का तर्क था कि चूंकि हमारे पास सभा को आयोजित करने के लिए कार्यकर्ता नहीं हैं, इसलिए अच्छी जनसभाएं नहीं हो पा रही हैं। आरिफ का तर्क था कि जनता के बीच हम लोगों के मुद्दे साफ नहीं हुए हैं। केवल भ्रष्टाचार और व्यवस्था बदलने के मुद्दे जनता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अरुण नेहरू का कहना था कि जब तक सीधी-सीधी सत्ता की राजनीति नहीं की जायेगी, तब तक जनता हमारे साथ नहीं आयेगी। उ०प्र० या किसी अन्य राज्य में घुसपैठ करके सरकार को हम लोग नहीं गिरा देते हैं, तब तक 'टेम्पो' नहीं बनेगा। सत्यपाल मलिक ने अरुण नेहरू की हां-में-हां मिलायी।

पता चला है कि वी०पी० सिंह इसके बाद पुराने समाजवादी नेता मधु लिमये से अपने जनमोर्चा के लिए दिशा लेने के लिए मिले। वी०पी० सिंह के मन में एक और प्रश्न था कि अगर राजीव गांधी दलबदल कानून में संशोधन करके जनमोर्चा के सांसदों और विधायकों की संसद या विधानमंडल की सदस्यता को समाप्त करा देते हैं, तो क्या किया जाये? बताते हैं कि मधु लिमये ने उनको सलाह दी कि वह अपने जनमोर्चा में लोहिया-नरेन्द्र देव विचारधारा के लोगों को शामिल करें, इससे मोर्चे का आधार भी बढ़ेगा और अदालत में राजीव गांधी के ऐसे किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि संविधान में विचार को व्यक्त करने की मूल आजादी है। कहा जाता है कि रामधन और वी०पी० सिंह के संयुक्त हस्ताक्षर से इंका महामंत्री केदार नाथ सिंह के जवाब में जो बयान दिया था, उसको मधु लिमये ने ही तैयार किया था। केदारनाथ सिंह का बयान था कि सरकार को दलबदल कानून में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें पार्टी से निकाले गये सांसदों और विधायकों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाये। सरकार का कानून मंत्रालय इस सुझाव पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। पिछले दिनों इंका की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर विचार होना था, लेकिन राजीव गांधी के पास समय नहीं था, इसलिए विचार नहीं हो पाया। वैसे इसको कार्यकारिणी की विचार सूची में शामिल कर लिया गया था।

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि वी०पी० सिंह मधु लिमये से निकट का संबंध बनाये हुए हैं और बराबर राय ले रहे हैं। कहते हैं कि वी०पी० सिंह ने पिछले दिनों बुद्धिजीवियों को अपने पक्ष में लाने का जो गुप्त अभियान चलाया है, उसके पीछे भी मधु लिमये की ही राय है। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मधु लिमये को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है?

अर्जुन सिंह के खिलाफ मुहिम

केंद्रीय संचार मंत्री अर्जुन सिंह की राजनीतिक परेशानियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। चुरहट लाटरी का मामला अंदर-ही-अंदर तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री राजीव गांधी को म०प्र० के डिप्टी आडीटर जनरल की वह रिपोर्ट दिखायी गयी, जिसमें चुरहट लाटरी के घोटाले का विस्तृत ब्यौरा है। दिल्ली के प्रायः हर राजनीतिक दलों के कार्यालयों तथा इस विषय में रुचि रखने वाले इंकाई सांसदों के हाथों में म०प्र० के डिप्टी आडीटर जनरल की रिपोर्ट है। राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को वितरित करने का काम मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को खुश करने या उनके इशारे पर म०प्र० के युवा इंकाई सांसद सुरेश पचौरी कर रहे हैं।

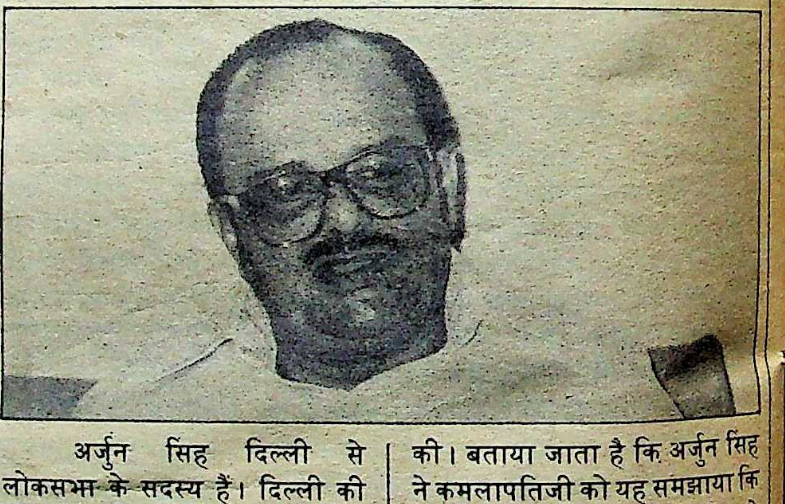

अर्जुन सिंह दिल्ली से लोकसभा के सदस्य हैं। दिल्ली की राजनीति में उनकी खुली जूती-पैजार केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हरकिशन लाल भगत से चल रही है। इसलिए अर्जुन सिंह से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए भगतजी की म०प्र० की अर्जुन सिंह बनाम मोतीलाल वोरा राजनीति में गहरी रुचि हो गयी है। भगत पिछले कई महीनों से यह प्रचारित कर रहे हैं कि अर्जुन सिंह, पूर्वमंत्री तथा जनमोर्चा के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह से गुप्त संबंध बनाये हुए हैं। इस राजनीति में भगतजी ने केंद्रीय रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत को भी साथ लेने का काफी चक्कर चलाया, लेकिन अंत में पंतजी इस लफड़े में नहीं फंसे। पंतजी भी दिल्ली से लोकसभा के सदस्य हैं।

ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जुन सिह इन दिनों काफी परेशान हैं। लेकिन उनके चेहरे से परेशानी भांप लेना आसान काम नहीं है। इंका महामंत्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी को पिछले दिनों राजीव गांधी ने राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने के लिए भोपाल भेजा था। कहा जा रहा है कि चतुर्वेदी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी है, उसमें अर्जुन सिह विरोधी स्वर साफ उभर कर आया है। चतुर्वेदी पं० उमाशंकर दीक्षित के खास आदमी माने जाते हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि अर्जुन सिह की राजनीतिक समझ बहुत परिपक्व है। पिछले दिनों १५ नवम्बर को अर्जुन सिंह अचानक पं० कमलापति त्रिपाठी के ६, जनपथ स्थित बंगले पर पहुच गये। उन्होंने जाते ही पंडितजी के चरणों को छुआ और करीब एक घंटे तक उनसे बात की। बताया जाता है कि अर्जुन सिंह ने कमलापतिजी को यह समझाया कि जब वह इंका के उपाध्यक्ष थे, तो माखनलाल फोतेदार के इशारे पर उनके खिलाफ मुहिम चलायी गयी थी। उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। फोतेदार उनका मात्र इस्तेमाल कर रहे थे। पंडितजी उन दिनों इंका के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे। पंडितजी ने अर्जुन सिंह के इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। कहा जा रहा है कि अर्जुन सिंह कमलापतिजी को इस बात के लिए तैयार करने गये थे कि वह पं० उमाशंकर दीक्षित से मोर्चा लें। यह तो अभी पता नहीं चला है कि कमलापतिजी इसके लिए तैयार हो गये हैं या नहीं। लेकिन अर्जुन सिंह और कमलापतिजी के बीच अंदर-ही-अंदर कुछ पक जरूर रहा है।

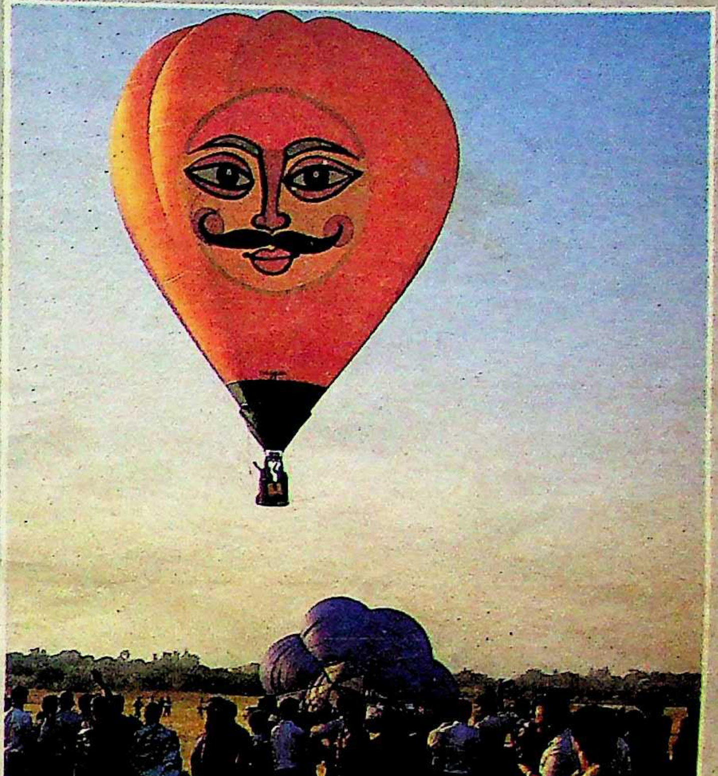

ये चित्र हैं, राजधानी नयी दिल्ली में आयोजित तीसरे 'इंडिया इंटरनेशनल बैलून मेले' के। हर वर्ष आयोजित होने वाले 'बैलून मेले' में इस साल भारत के अलावा अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पाकिस्तान, प० जर्मनी, हंगरी, डेनमार्क, मिस्र, स्विट्जरलैंड आदि देशों ने भी हिस्सा लिया।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

CAMERON BALLOONS
CHAL

५ नवंबर, ८७ को इंडियन एक्सप्रेस के हड़ताली कर्मचारियों पर भारतीय जनता पार्टी के हमले के विरोध में संसद के सामने प्रेस कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला।

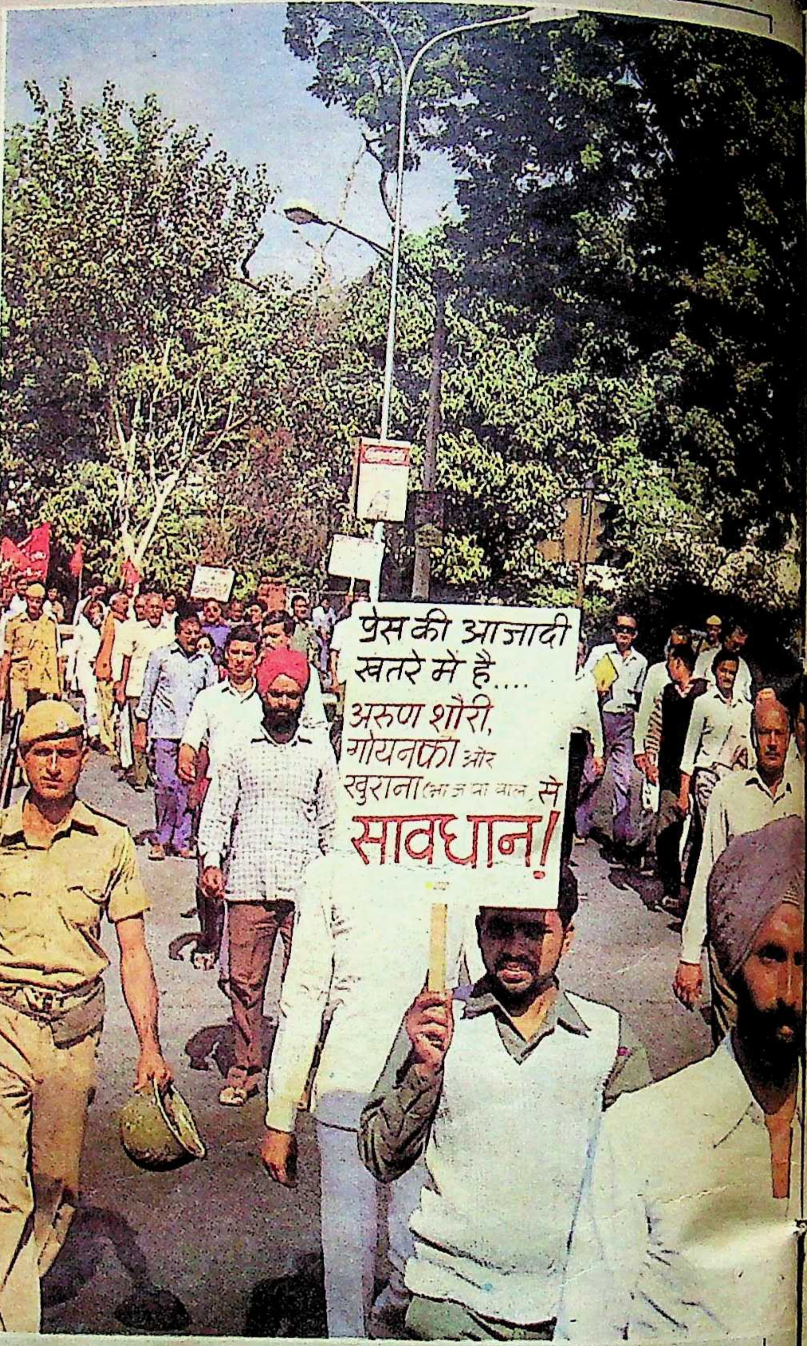
प्रेस की आज़ादी
खतरे में है....
अरुण शौरी,
गोयनका और
खुराना
से
सावधान!

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

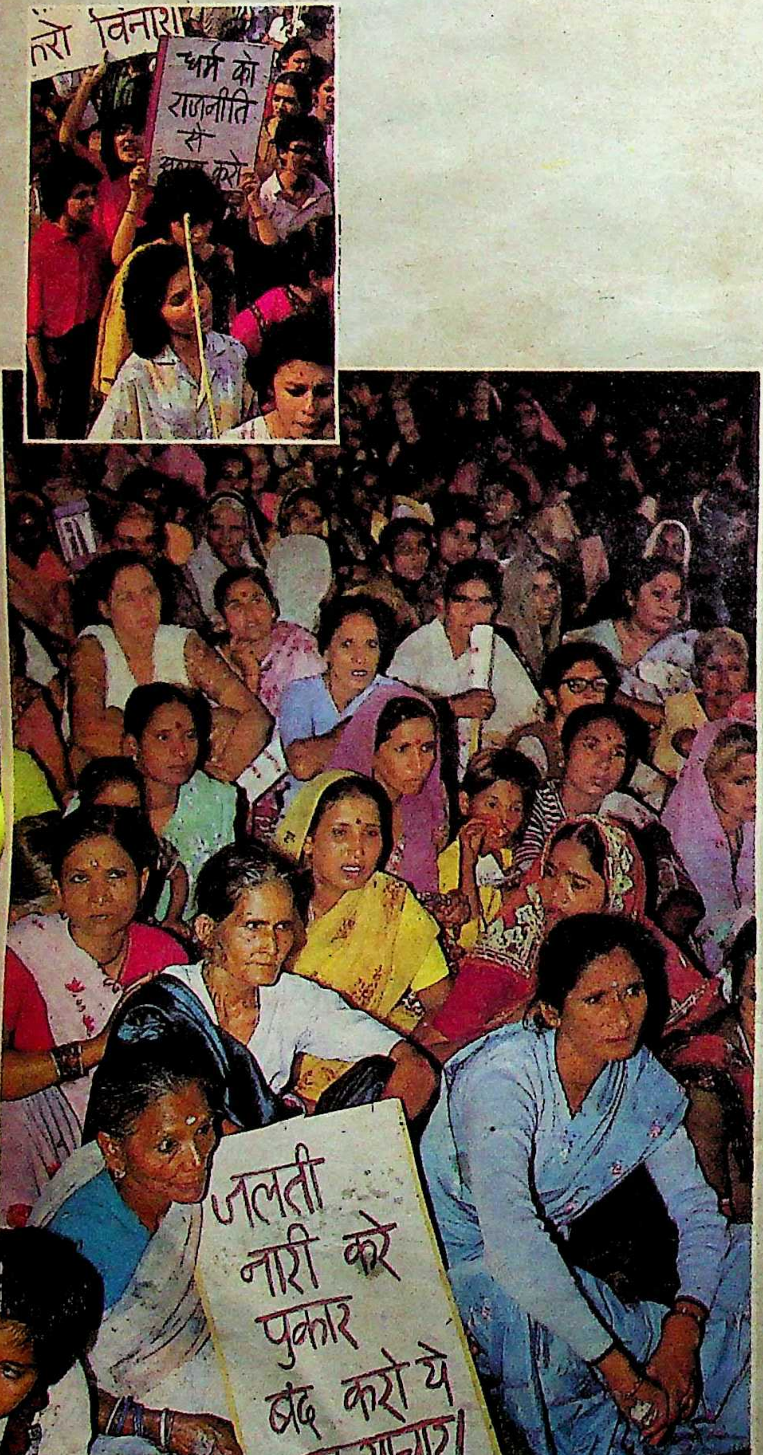
तरो विनाश
धर्म को
राजनीति
से
जलती
नारी के
पुकार
बद करो ये
अत्याचार!

६ नवंबर को राजधानी में सती-प्रथा के विरोध में दिल्ली की छात्राओं-छात्रों सहित जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा, अ०भा० छात्र फेडरेशन, एस०एफ०आई० तथा अन्य महिला संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया।

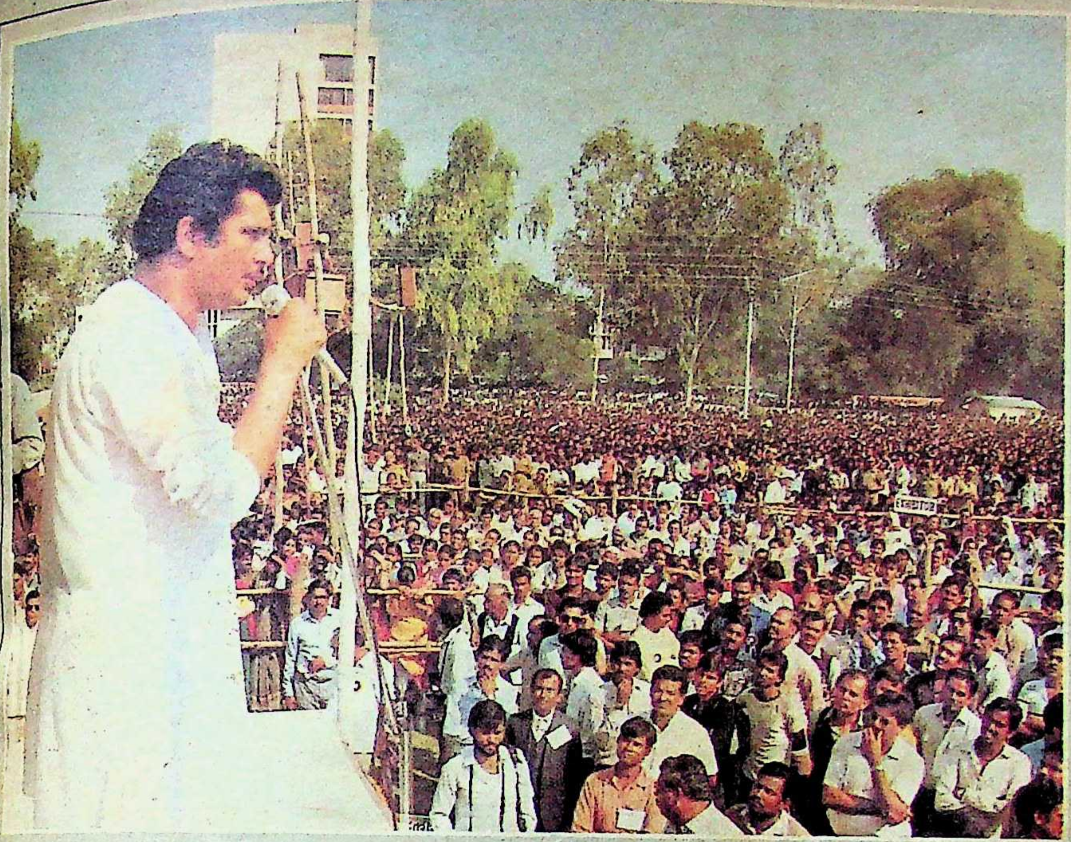

१६ अक्तूबर से शुरू हुई उत्तर प्रदेश के ८५० सिनेमाघरों की हड़ताल को, ११ नवंबर को लखनऊ में आयोजित विशाल रैली ने चरम पर पहुंचा दिया। विभिन्न फिल्म-संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली में कई नामी फिल्मी हस्तियों (राज बब्बर, फारूख शेख, रजा मुराद, विजय आनंद और फिल्म निर्माता जी०पी० सिप्पी) ने हिस्सा लिया।

हड़तालियों की मांग है कि १५० प्रतिशत मनोरंजन टैक्स को घटाकर पांच से पच्चीस प्रतिशत तक किया जाये तथा सिनेमा को उद्योग का दर्जा देकर बिजली की दरें छोटे उद्योग जैसी की जायें। इस हड़ताल के चलते दो करोड़ रुपए प्रति सप्ताह की चपत सरकारी खजाने को पड़ रही है। सिनेमाघरों से जुड़े एक लाख कर्मचारी सड़क पर आ गये, सो अलग!

छाया : मनमोहन शर्मा

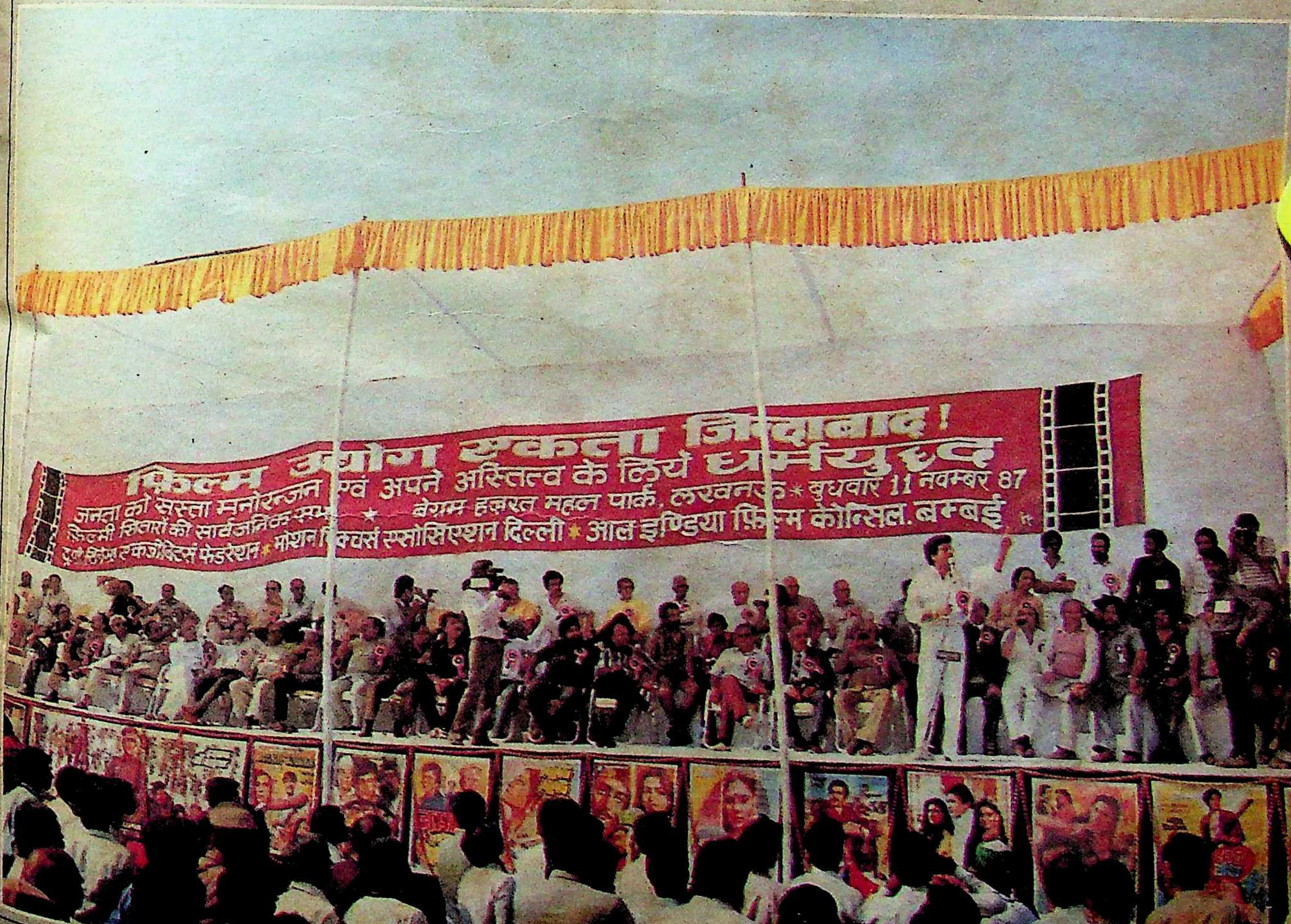
फिल्म उद्योग एकता जिंदाबाद!
धर्मयुद्ध
अपने अस्तित्व के लिये
जनता को सस्ता मनोरन्जन एवं
बुधवार 11 नवम्बर 87
बेगम हज़रत महल पार्क, लखनऊ
फिल्मी सितारों की सार्वजनिक सभा
आल इण्डिया फिल्म कौंसिल, बम्बई
मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन दिल्ली
फेडरेशन

१४ नवंबर यानी चाचा नेहरू का जन्म दिन, पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। दिल्ली में आयोजित ऐसी ही एक चित्र-प्रतियोगिता में भाग लेते बच्चे।

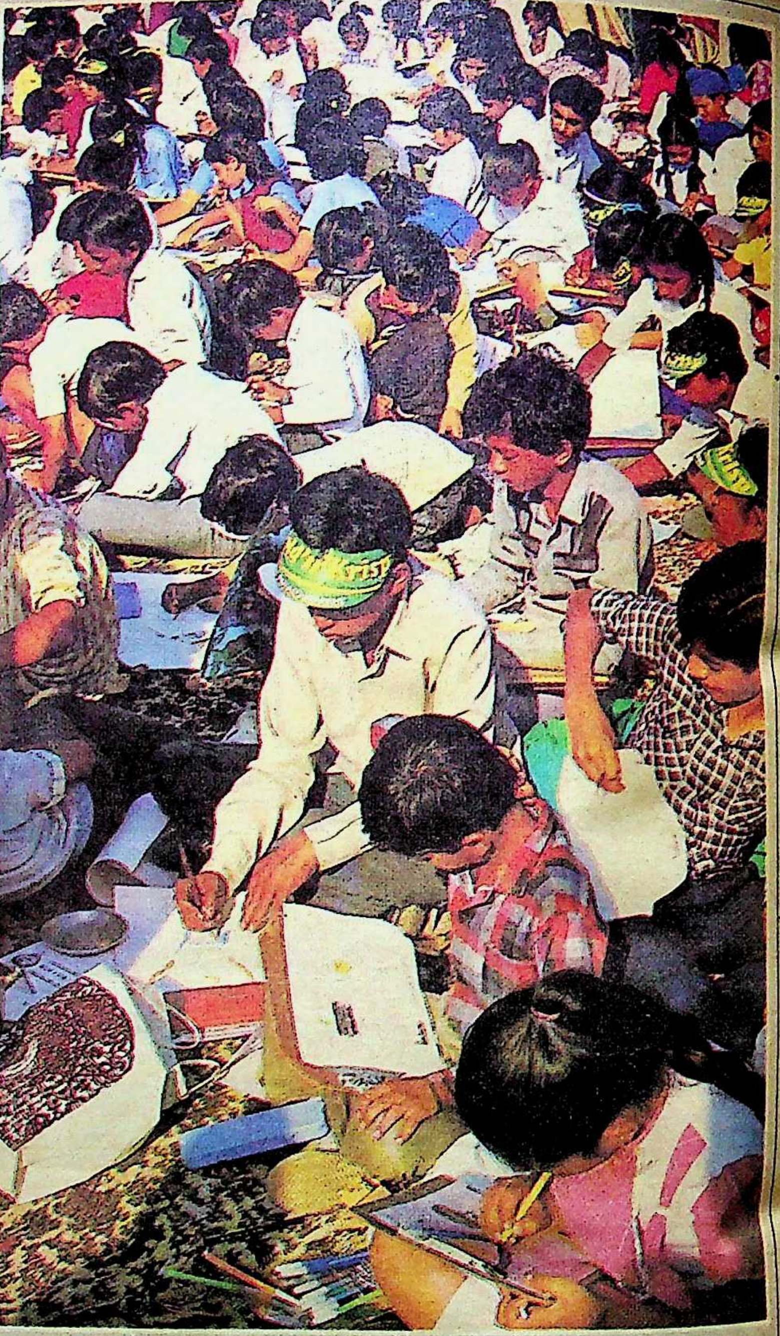

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

छाया : मनमोहन शर्मा

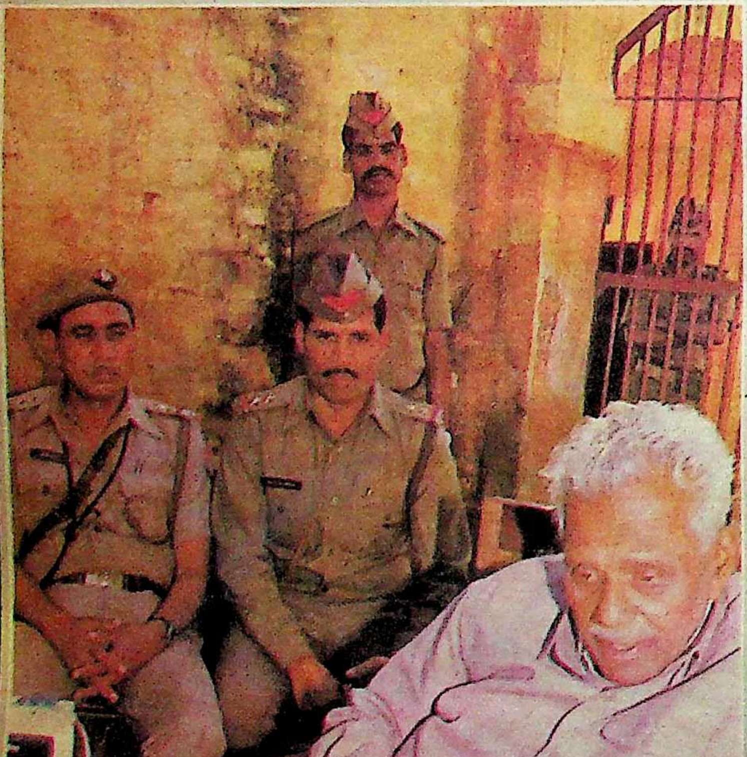

ठगी की दुनिया में एक 'मिथ' बन जाने वाले और पुलिस को बार-बार चकमा देने वाले ७३ वर्षीय नटवरलाल को आखिर बनारस में गिरफ्तार कर लिया गया। कई नामों से ठगी करने वाले नटवरलाल की निगाह में ठगी एक कला है और जेल से छूटकर वह फिर अपने इसी 'धंधे' में लग जायेगा। उसका दावा है कि मैं स्वेच्छा से पकड़ा जाता हूं और कोई भी जेल मुझे दो—तीन महीने से ज्यादा बंद नहीं रख सकती। यदि नटवरलाल के सभी अपराधों की सजा जोड़ी जाये, तो २०० वर्ष से ऊपर बैठती है। इतने साल तो वह जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सवाल यह है कि जब तक जिंदा है, तब तक क्या वह जेल की दीवारों में बंद रह पायेगा?

झूठ का रिश्ता

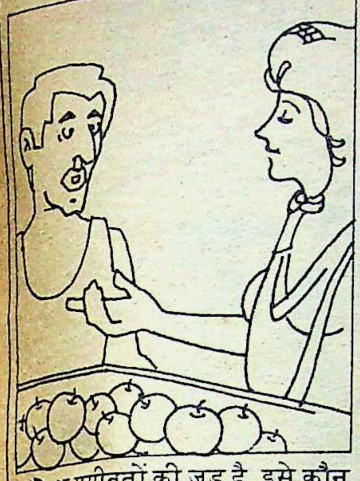

लोभ मुसीबतों की जड़ है, इसे कौन नहीं जानता, फिर भी लोभ में पड़कर लोग मुसीबतों को दावत देते ही रहते हैं। तंजावुर रेलवे स्टेशन का एक २० वर्षीय फल-विक्रेता रमन दो मुस्लिम महिलाओं को फल बेचने के लोभ में ऐसी बात बोल बैठा जो उसकी जान का जंजाल बन गयी। उन महिलाओं ने उससे पूछा था कि क्या वह नवाबजान है? जब उसने उन्हें खुश करने के लिए 'हां' कहा, तो वह नहीं जानता था कि वह एक बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है।

वे महिलाएं खुश ही नहीं, बेहद खुश हुईं, क्योंकि उनका एक संबंधी नवाबजान पिछले १० सालों से लापता था और रमन की शक्ल भी नवाबजान से मिलती-जुलती थी। फिर क्या था, वे महिलाएं उसे अपने साथ ले चलने की जिद्द करने लगीं। अब तो रमन की हालत देखने काबिल थी। वह कसम खा-खाकर कह रहा था कि वह पास की ही कालोनी में रहनेवाला हिंदू रमन है, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं थीं। उस वक्त भीड़ इकट्ठी हो जाने के कारण वे महिलाएं चली गयीं, लेकिन अगले ही दिन अपने परिवार के पुरुष सदस्यों को लेकर वे रेलवे स्टेशन पर फिर जा धमकीं। अब तो रमन का और भी बुरा हाल था। अपने को रमन साबित करने के लिए वह अपने तीन छोटे भाइयों को भी ले आया, लेकिन मुस्लिम परिवार उसे नवाबजान ही मानता रहा और उसे अपने साथ ले जाने पर आमादा था। जब जोरजबरदस्ती से काम नहीं चला, तो उन्होंने रमन को ले जाने के लिए उसके माता-पिता को मुंहमांगी रकम देने की पेशकश की, लेकिन उसके माता-पिता कुछ पैसों के बदले अपने पुत्र को उन्हें क्यों सौंपते?

पता चला है कि वह मुस्लिम परिवार अभी भी रमन को नवाबजान ही मानता है और आये-दिन रमन के घर पहुंच जाता है। रमन की समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाये।

ब्लू फिल्म को हरी झंडी

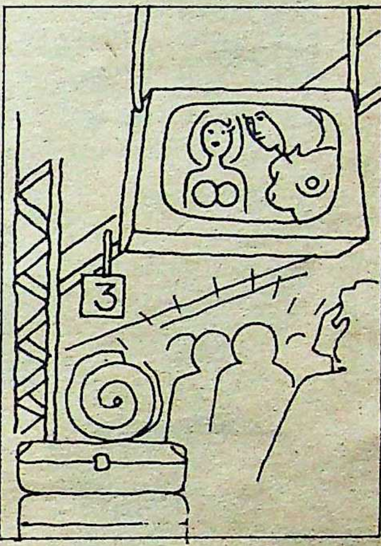

अपराध-शास्त्र का एक सिद्धांत यह भी है कि शातिर-से-शातिर अपराधी से भी कोई-न-कोई ऐसी चूक अवश्य होती है, जो उसे हवालात पहुचा देती है। पटना रेलवे स्टेशन पर स्थापित क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रसारण केंद्र के स्टूडियो में रात्रि में ब्लू (अश्लील) फिल्मों का वर्षों से चोरी-छिपे आनंद उठा रहे, कई रेलवे कर्मचारी और अफसर अपनी एक चूक के कारण पुलिस की गिरफ्त में आ गये।

दो नवंबर को बड़े सबेरे करीब चार बजे पटना रेलवे स्टेशन के एक और दो नंबर के प्लेटफार्मों पर यात्री पंजाब मेल और नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तंभी प्लेट फार्मों पर लगे दर्जनों क्लोज सर्किट टेलीविजन सेट चमक उठे। यात्रियों ने समझा कि उक्त ट्रेनों के समय के संबंध में कोई जानकारी प्रसारित होने वाली है, लेकिन उन टेलीविजन सेटों पर जो कुछ प्रसारित हुआ, उससे सभ्य और सज्जन लोगों की आंखें झुक गयीं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं थी, जिनकी बांछे टेलीविजन सेटों पर आ रहे दृश्यों को देखकर खिल उठी थीं। उस समय टेलीविजन पर कोई ब्लू फिल्म आ रही थी, जिसमें अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा था। पूरे दस मिनट तक अश्लील क्रियाओं के दृश्य टेलीविजन पर आते रहे। स्टेशन पर उपस्थित रेलवे के आला अफसरों में भगदड़ मच गयी। रेलवे के कुछ अफसर और क्रोधित यात्री प्रसारण स्टूडियो जा धमके। चपरासी को धर-दबोचा गया। तब कहीं जाकर यह प्रसारण बंद हुआ। बाद में राज खुला कि रेलवे स्टेशन का यह स्टूडियो एक लंबे अरसे से रात्रि ९ बजे से लेकर सुबह ५ बजे तक ब्लू फिल्में दिखाने का अड्डा बना हुआ था, जहां शहर के कई रसिक पुरुष और महिलाएं भी अश्लील फिल्में देखा करती थीं तथा वहां शराब और साकी का भी इंतजाम होता था। उस दिन उन लोगों से सिर्फ एक चूक यह हो गयी थी कि वे प्लेटफार्मों पर लगे टेलीविजन सेटों के स्विच बंद करना भूल गये थे।

आप्रवासी सिक्के

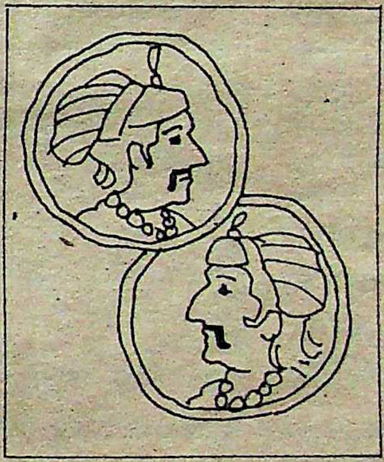

अंग्रेजों की विदाई के समय १९४७ में जब भारत की गरीबी की बात उठती थी, तो मजाक में कहा जाता था कि महमूद गजनी से लेकर अंग्रेजों के काल तक भारत से जितनी सम्पदा विदेशी लूट और धोखे से ले गये हैं, यदि वह सबकी-सब वापस आ जाये, तो भारत विश्व का सबसे अमीर और समृद्ध देश बन जाये। हाल ही स्विट्जरलैंड में मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां द्वारा निर्मित ठोस सोने के क्रमशः १२ एवं १.१ किलो वजनी दो सिक्कों की नीलामी की खबर से उक्त मजाक हकीकत नजर आने लगता है। १२ किलो के सिक्के की ८० लाख डालर तथा १.१ किलो सिक्के की ३० लाख डालर बोली लग चुकी है। इसके मालिक का नाम-पता गुप्त रखा गया है। भारत सरकार इन सिक्कों को वापस लाना चाहती है। उसकी कोशिश है कि ये सिक्के नीलाम न होने पायें। साथ ही वह यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि ऐसे और कितने सिक्के विदेश में हैं। बहरहाल, भारत सरकार फिलहाल विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का ही धन वापस ले आये, तो भारत की आर्थिक दशा बहुत कुछ सुधर जाये। विदेश पहुंच गयी सदियों पुरानी सम्पदा को वापस लाना वैसे भी उसके बस में नहीं है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अभी तक भी ब्रिटिश ताज में जड़ा हुआ है।

कलियुगी सुपरमैन

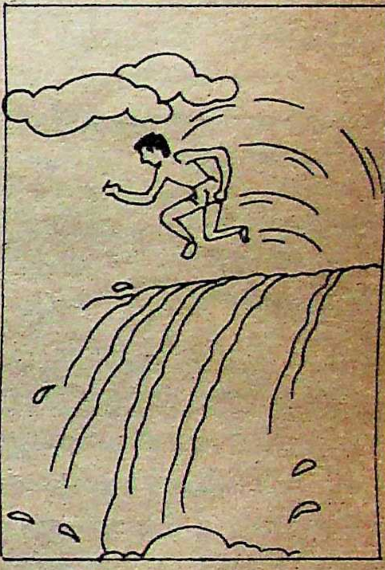

बंबई निवासी २९ वर्षीय धनंजय शर्मा ने घोषणा की है कि वह अगले वर्ष जुलाई-अगस्त में अमरीका और कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात नियागरा में छलांग लगायेगा। उनका इरादा आत्महत्या करने का नहीं है। उनका दावा है कि वह मरेंगे नहीं, बल्कि सफल छलांग लगाकर विश्व रिकार्ड कायम करेंगे। वैसे भी धनंजय शर्मा पिछले दस वर्षों से अनेक रोमांचक कामों को अंजाम दे चुके हैं। १९७६ में उन्होंने साढ़े चार घंटे में १९४ कप चाय पी डाली थी। अपना सबसे ताजा करिश्मा उन्होंने गत २९ अक्तूबर को दिखाया। वह दस घंटे में दो किलो, छह सौ ग्राम शीशा चबाकर खा गये। फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। देखना है, भारत और अमरीका सरकार उन्हें नियागरा जलप्रपात में छलांग लगाने की अनुमति देती है या नहीं।

—संकलन : विनोद मिश्र

शरद जोशी

किसानों को बोतल में बंद जिन समझते हैं

१९६७ तक भारतीय डाक सेवा में रहने के बाद ६ वर्ष तक शरद जोशी स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन मार्च, १९८० में पूना में प्याज उत्पादकों के आंदोलन से वह बड़ी तेजी से किसान-आंदोलन के तेज-तर्रार नेता के रूप में उभरे हैं। 'रास्ता रोको' और 'रेल रोको' आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध शरद जोशी ने घोषणा की है कि वह किसानों की न्यायोचित मांगें मनवाने के लिए बजट सत्र के दौरान १२ मार्च, १९८८ को ५० लाख किसानों की दिल्ली में रैली आयोजित करेंगे। यों शरद जोशी अपने को अराजनीतिक कहते हैं, लेकिन १९८४ के संसदीय निर्वाचन में उन्होंने शरद पवार व जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया था। हाल में वह विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके जनमोर्चा को समर्थन-सहयोग दे रहे हैं। किसान समस्या और किसानों की शक्ति के संदर्भ में शरद जोशी से ***रंजना कक्कड़*** *ने बातें की हैं। बातचीत के अंश :*

सरकार हिंसा भड़काने में दिलचस्पी रखती है : शरद जोशी

माया : आप 'इंडिया' और 'भारत' के बीच भेद क्यों करते हैं? रिजर्व बैंक के विशेष अध्ययन में तो बताया गया है कि देश की औसत वास्तविक संपत्ति के मामले में गांव-शहरों में कोई खास असमानता नहीं है।

शरद जोशी : भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर कुछ कहने के पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि बुनियादी गलती रिजर्व बैंक ने नहीं, बल्कि 'हिंदुस्तान टाइम्स' के संवाददाता ने की। उसने रिपोर्ट देते हुए यह मान लिया कि भारत और ग्रामीण भारत एक समान हैं और इसी प्रकार इंडिया और शहरी भारत समान हैं। यह कतई नहीं है। यदि मुझे ग्रामीण भारत की बात करनी है, तो मैं केवल ग्रामीण भारत ही कहूंगा—भारत नहीं और मैं शहरी भारत को भी भारत नहीं कहूंगा। मैं इस नयी अवधारणा की इस प्रकार दो-टूक व्याख्या करता हूं : इंडिया-वह भाग, वह राष्ट्रीय सचाई है, जिसने अंग्रेजों से आर्थिक और शैक्षिक लाभ उत्तराधिकार में प्राप्त किया है और भारत—वह राष्ट्रीय सत्य है जो अंग्रेजों की रवानगी के बाद भी दुबारा शोषण की चक्की में पीसा जा रहा है। यह सीमा रेखा चुंगी चौकी जैसी नहीं है, जिसके इस ओर गांव और उस ओर शहर है। मसलन चीनी मिलों के अध्यक्ष भी इंडिया से संबंधित नहीं हैं, भले ही वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों, जबकि शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों व फुटपाथों के वासी दरअसल शरणार्थी किसान हैं, जो भारत में अपना पेट पालने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इंडिया आ गये हैं। किंतु रिजर्व बैंक के आंकड़ों में इन सबका घालमेल कर दिया गया है।

माया : आप 'किसान' की व्याख्या कैसे करेंगे?

जोशी : मुझे 'किसान' शब्द की व्याख्या नहीं करनी है। मुझे 'शेतकारी' शब्द का खुलासा करना है। मराठी में इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो खेती से जुड़ा हो। इसका भूमि की मिल्कियत से संबंध नहीं है। जो भी व्यक्ति कृषि पर जीवन गुजारता है वह 'शेतकारी' है। इस व्याख्या के तहत एक सांसद के पास मुमकिन है भूमि हो, पर यदि वह उस पर जिंदगी नहीं गुजारता, तो वह किसान नहीं माना जायेगा। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति, जिसके पास भूमि नहीं है, पर उस पर जिंदगी गुजारता है, तो वह एक 'शेतकारी' कहा जायेगा। 'शेतकारी' का शाब्दिक अर्थ है—वह व्यक्ति जो भूमि-'शेत' (क्षेत्र) पर काम करता हो। इसी अर्थ में संगठन का नाम रखा गया है।

माया : सरकार का कहना है कि आपकी लाभकारी मूल्यों की प्रणाली और मसले उठाने का तरीका अवैज्ञानिक है। क्या आप इससे सहमत हैं?

जोशी : मैं सरकार से एक सवाल का जवाब चाहता हूं। एक वर्ष में सरकार के कृषि मूल्य आयोग ने एक हेक्टर गेहूं पर कीटनाशक छिड़कने की लागत एक पैसा आंकी है। क्या यह सरकार का लागत आंकने का वैज्ञानिक तरीका है? आज भी हालत यह है कि किसान जब खाद खरीदता है, तो सरकार एक गाड़ी (बैलगाड़ी) खाद की लागत महज ३ रुपए आंकती है, किंतु दूध उत्पादक जब खाद बेचता है, तो सरकार उतनी ही मात्रा की खाद से होने वाले लाभ को ३५ रुपए मानती है। मैं नहीं समझता कि सरकार उत्पादन लागत की वैज्ञानिक गणना की बात करने में सक्षम है। यदि सरकार की गणना वैज्ञानिक है, तो जिन सरकारी फार्मों को बीज और पानी (सिंचाई) उपलब्ध हैं, वे घाटे में क्यों चल रहे हैं? हमने सरकार को सुझाव दिया था कि वह कृषि मूल्य आयोग पर ऐसे प्रदर्शन-फार्मों को खोलने की

जिम्मेदारी डाले जहां यह दिखाया जा सके कि सरकार-एक क्विंटल गेहूं की जो खरीद कीमत १७१ रुपए दे रही है, तो उतनी ही कीमत पर वह उगाया भी जा सकता है।

माया: कृषि राज्यमंत्री योगेन्द्र मकवाना का कहना है कि आपने बातचीत के बार-बार के प्रस्ताव ठुकरा दिये हैं।

जोशी: मैं चाहता हूं कि योगेन्द्र मकवाना एक भी ऐसा पत्र दिखा दें जो उन्होंने मुझे लिखा हो या एक भी आमंत्रण-पत्र मुझे दिखा दें जो भेजा हो। जब कभी विचार-विमर्श की संभावना होती है मैं एस०बी० चह्वाण के पास जाता हूं। मैं प्रधानमंत्री तक से मिलने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है कि उस व्यक्ति को जानकार होना चाहिए। इसलिए मैं किसी अन्य व्यक्ति से मिलना पसंद करूंगा। किंतु वह (मकवाना) एक भी ऐसा पत्र दिखा दें जिससे सिद्ध हो कि उन्होंने मुझे बुलाया था।

माया: जो किसान शक्ति उभरी है, उसमें आपके संगठन की क्या भूमिका है?

जोशी: मेरे विचार से हमने किसान शक्ति के इस उदय को मुहावरा मुहैया किया है। पुराने समय में किसानों की बात करने वाले लोग किसान समुदाय की आपसी लड़ाई के लिए उनके दो समूह बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने किसानों को साहूकारों-जमींदारों और गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के खिलाफ संगठित किया। किसी ने भी समूचे कृषक समुदाय को एकजुट करने और उनके दिमाग में यह बात लाने का प्रयास नहीं किया कि ये संघर्ष उनकी बाहरी दुनिया की लड़ाई की तुलना में कुछ नहीं, जिसे मैं इंडिया के नाम से पुकारता हूं।

दूसरी बात, हमने किसानों को अपने पर गर्व करना सिखाया है। अभी तक यह दृष्टिकोण था कि 'किसानों के साथ परोपकार और दया का बरताव' करो। हमने उन्हें बताया है कि अपने अधिकारों को पहचानो और उसकी प्राप्ति की आशा करो। इसका अर्थ है तुम्हारे वास्तविक कार्य का वैध पारिश्रमिक।

माया: आप कैसे यह गारंटी देंगे कि इस किसान शक्ति का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग नहीं होगा?

जोशी: जब ७० प्रतिशत लोग जागृत हो रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत सत्ता के लिए दुरुपयोग करना बड़ा मुश्किल है। किसानों के हितों का व्यक्तिगत राजनीतिक लाभों में इस्तेमाल करने का खतरा हमेशा ही रहा है। १९८० में मेरे द्वारा शुरू किये गये आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि किसान अपने काम और हुनर के बदले महज वाजिब कीमत के लिए संघर्ष कर रहा था, ताकि उसका शोषण बंद हो जाये।

माया: आप जिस 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है?

जोशी: यह हम लोगों द्वारा १० वर्षों से संचालित आंदोलन का एक प्रकार का चरमोत्कर्ष है। हम थोड़ा-थोड़ा करके अपनी मांगों में समुचित बढ़ोत्तरी करते रहे हैं। जब उत्पादन लागत बहुत अधिक थी, तो प्रायः हमने कम मांग की, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को डांवाडोल नहीं करना चाहते थे। सरकार एक वक्त ऐसे चरण में पहुंची थी कि वह कृषि मूल्य आयोग का माम और कामकाज बदलने पर राजी हो गयी थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनवरी, १९८४ में घोषणा की थी कि कृषि मूल्य आयोग (ए०सी०पी०) का नाम बदल कर केन्द्रीय कृषि मूल्य आयोग (सी०ए०सी०पी०) रखा जायेगा और इसकी कार्यविधि में तीन माह में परिवर्तन किया जायेगा। अब वह कहते हैं कि सी०ए०सी०पी० के कामकाज का तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। यह मौजूदा प्रधानमंत्री की पहली बेईमानी है।

अब जबकि मकवाना ने कहा है कि कृषि में जोखिम के मुद्दे को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, तो किसानों का मत है कि वर्तमान शासक 'काले अंग्रेज' हैं। इनकी नीतियां उपनिवेशवादी हैं और इसलिए किसान आर्थिक स्वाधीनता के सिंहनाद के लिए दिल्ली आयेंगे। यह कोई मांगपत्र पेश करने का अवसर नहीं होगा, बल्कि समूचे देश के ५० लाख किसान यहां आयेंगे और चार प्रमुख बातों की घोषणा करेंगे। एक, सरकार ने हमें लाभकारी मूल्य देने से लगातार इनकार किया है। वह ऐसी कोशिश करती रही है जिससे हमे लाभकारी मूल्य प्राप्त न हो पाये। अगर लाभकारी मूल्य नहीं मिलता तो किसान तमाम कृषि पैदावारों की आपूर्ति रोक देंगे। वे महज अपने लिए और अपने खेतों पर काम करने वालों के लिए पैदावार करेंगे। दूसरी, हम अपने कर्जों की अदायगी नहीं कर सके, क्योंकि सरकार एक किसान-विरोधी मूल्य नीति अपनाती रही है जिससे कृषि कर्ज में डूबी रही। ठेका कानून के तहत जब ठेके की एक पार्टी प्रबंध से मुकरने का कदम उठाती है, तो ठेका रद्द हो जाता है। इसलिए कर्ज के ठेके गैरकानूनी और अनैतिक हैं और हम ऐलान करते हैं कि हम सरकार के कतई देनदार नहीं हैं। सरकार खुद कहीं अधिक हमारी देनदार है। तीसरी बात सूखे से संबंधित है। अच्छी वर्षा का लाभ पूरा देश उठाता है। सूखे की मार केवल किसान सहता है। तब किसान और उसका परिवार पत्थर तोड़ता और अन्य काम करता है। हम कह चुके हैं कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हम शहरों में मार्च करके अपने शहरी भाइयों के साथ जीवन की आवश्यकताओं का मिल-बांटकर उपयोग करेंगे। हमारी चौथी मांग खेत मजदूरों से संबंधित है। प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी और पत्रकार जहां सदैव ऊंचे-से-ऊंचे वेतनों की मांग करते हैं, वहीं खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का हिसाब हमेशा उनकी कैलरी जरूरतों के आधार पर होता है। यह सरासर गलत है। गणना का सही तरीका होगा, 'जय जवान जय किसान' फार्मूला। यदि आप जवान और किसान को एक बराबर मानते हैं, तो किसान को कम-से-कम उतना तो मिलना ही चाहिए जितना जवान को उसके सेना में भर्ती के दिन मिलता है जो आज २५ रुपए रोजाना है। इसलिए हमने मांग की है कि खेत मजदूर की न्यूनतम रोजाना मजदूरी २५ रुपए होनी चाहिए। यह २५ रुपए कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गयी लागत गणना में जोड़ी जानी चाहिए। इन चार बातों की मांग हम 'दिल्ली चलो' मोर्चा में करेंगे।

जब लोगों की
तादाद कम होती है,
तभी लोग हिंसक बन जाते हैं।
जब हमारी तादाद ज्यादा होती है, तो
हमें हिंसक होने की जरूरत ही
नहीं होती।

माया: आप विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनमोर्चा के संपर्क में कैसे आये?

जोशी: शेतकारी संगठन अथवा अंतरराज्यीय समन्वय समिति संपूर्ण रूप में आंदोलनकारी समितियों का गठन करती है। हम समझते हैं कि सत्ता में परिवर्तन मात्र से समस्याएं हल होना संभव नहीं। किंतु आंदोलनकारी समितियों के रूप में हम बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते। हम सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। पर इसकी एक बहुत अहम पूर्व शर्त यह है कि सरकार भी असैनिक सरकार होनी चाहिए। जैसाकि महात्मा गांधी कहा करते थे कि उनके सत्याग्रह को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि अंग्रेजों में ईमानदारी की भावना सन्निहित है। अब ईमानदारी और लोकतांत्रिक संतुलन व्यवहार रूप में भारत से गायब हो चुका है। फिलहाल हम समझते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह संभवतः भारतीय राजनीति में एक संतुलन कायम करने की दिशा में सर्वाधिक आशा की पेशकश कर रहे हैं इसलिए हम उस विकल्प को परवान चढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई अन्य कारगर विकल्प उभरता है, तो हम उसे मदद देने के लिए तैयार हैं।

माया: आपका फिलहाल जनमोर्चा से किस प्रकार का संबंध है?

जोशी: मैं उसका सदस्य नहीं हूं। मैं मोर्चा की आलोचना करता हूं। यदि विचारों में समानता है, तो मैं उसे व्यक्त करता हूं। फिलहाल मेरे लिए यह अन्य संगठनों की तरह है।

माया: यदि राजीव गांधी आपसे संपर्क कर आपकी मांगें मानने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या आप अपना पक्ष बदल देंगे?

जोशी: यह एक काल्पनिक सवाल है। यदि राजीव गांधी हमारी मांगें मानने की पेशकश करते हैं, तो

आज, आप अपनी पत्नी को ज़िन्दगी में कई चीज़ों की चिन्ताओं से मुक्त रख सकते हैं।

आपकी पत्नी के लिए उसका घर ही उसकी दुनिया है। दिन रात काम करके वह उसे आपके लिए सजाती संवारती है.... घर की छोटी से छोटी चीज़ भी उसके लिए बड़ा महत्त्व रखती है। इतनी मेहनत और सावधानी से जुटायी गई गृहस्थी की सुरक्षा के लिए उसकी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं क्योंकि आप ही उस के सुरक्षा प्रतीक हैं।

एक कार्य करके आप उसे हज़ार चिन्ताओं से मुक्त रख सकते हैं, "उसकी दुनिया सुरक्षित है"— बता सकते हैं।

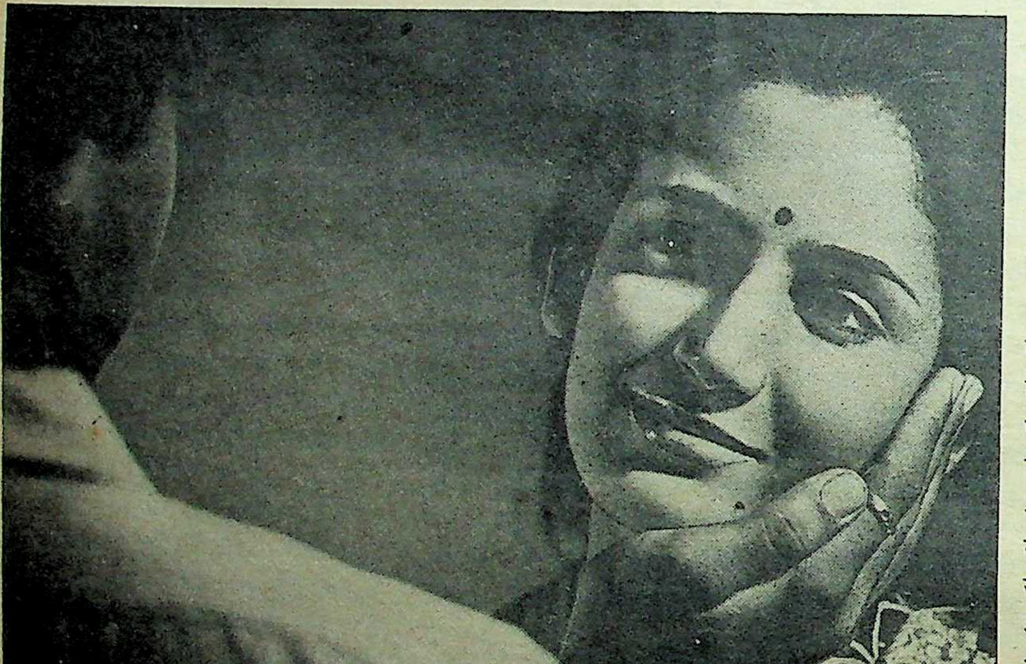

युनाइटेड इण्डिया की हाउसहोल्डर्स बीमा पॉलिसी— वो एक कार्य जो हज़ार भावनाओं के बराबर है।

हर समय घर में ताला लगाते समय हर नारी के मन में यही डर समाया रहता है कि हर चीज़ सुरक्षित रहेगी या नहीं। भला ऐसे डर की क्या ज़रूरत है?

युनाइटेड इण्डिया की हाउसहोल्डर्स बीमा पॉलिसी आपके घर को ऐसी सुरक्षा दे जो किसी ताले से नहीं मिल सकती। यह पॉलिसी आपके घर की चीज़ों को केवल चोरी के प्रति ही सुरक्षा नहीं देती बल्कि आग, बाढ़ व अन्य जोखिमों के प्रति भी सुरक्षा प्रदान करती है। आपके ज़ेवर-जवाहारात, टी.वी., साइकिल और अन्य घरेलू उपकरणों का भी बीमा करवाया जा सकता है। इसमें घर के स्थायी निवासियों को भी दुर्घटना के प्रति सुरक्षा दी जाती है..इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत अन्य जोखिमों के प्रति भी सुरक्षा शामिल है। जी हां, सिर्फ़ एक कार्य करके आप सभी चिन्ताओं से मुक्ति पा सकते हैं।

युनाइटेड इण्डिया में हम, लोगों और उनकी ज़रूरतों को सही तौर पर समझते हैं। आप उद्योगपति हों या भूमिहीन मज़दूर, फैक्टरी में काम करने वाले हों या मुर्गी-पालक कृषक, जहाज़ों के मालिक हों या ताड़ी खींचने वाले— हम तो देशभर में बिखरे अपने ९१५ शाखाओं के द्वारा सभी के पास पहुंचना चाहते हैं। उनकी विशेष ज़रूरतों के अनुसार पॉलिसियां बनाना चाहते हैं और उनके दावों को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं।

जी हां, जब तक जोखिम हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम हैं— युनाइटेड इण्डिया।

UNITED INDIA

युनाइटेड इण्डिया इन्श्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारतीय साधारण बीमा योजना निगम की एक सहायक कम्पनी)
२४ व्हाइट्स रोड, मद्रास-६०० ०१४

हरदिन, हर पल हम आपके साथ रहेंगे।

Mudra : M : UI : 3523 Hin

मुझे राजनीति में पड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं उससे दूर रहूंगा।

माया: विश्वनाथ प्रताप सिंह की टोली के कुछ लोगों को शंका है कि श्री सिंह महाराष्ट्र में आपकी लोकप्रियता का लाभ लेना चाहते हैं।

जोशी: महाराष्ट्र में विपक्ष में मेरे बाद नंबर दो समझे जाने वाले व्यक्ति को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने काफी काम किया है। किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह एकदम अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं। मेरे चुनाव लड़ने या सत्ता में कोई पद पाने की कोई मंशा नहीं। मैं किसान-कार्यकर्ता हूं। वह (श्री सिंह) राजनीतिज्ञ हैं।

माया: क्या आपका चरण सिंह से कोई संपर्क था? क्या आप उन्हें किसान नेता कहेंगे? उनकी भूमिका किसानों के संदर्भ में क्या उपयोगी रही है?

जोशी: मैं चौधरीजी को उनके जीवन के आखिरी तीन या चार वर्षों के दौरान ही जान पाया। मैं ऐसे चंद लोगों में था, जिन्होंने उन पर यह दबाव डालने की कोशिश की कि वह राजनीति छोड़कर पूर्णतया किसान आंदोलन में आ जायें। उनके लिए शायद जीवन के उस दौर में ऐसा करना संभव नहीं था। पर कोई भी उन्हें इस बात का श्रेय देने से इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने यह अहसास दिलाया कि किसान समस्या जैसी भी कोई चीज है। १९८० में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसको संभवत: चौधरीजी द्वारा डाली गयी बुनियाद पर ही खड़ा किया जा रहा है।

माया: आपके मार्च-आंदोलन कभी भी नीतियों को प्रभावित नहीं कर पाये। क्या आप समझते हैं कि मात्र संख्या के बलबूते पर आप नीति संबंधी फैसलों पर प्रभाव डाल पायेंगे?

जोशी: मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि दिल्ली में ऐसे मार्च जो पहले हुए हैं, उनका कोई असर पड़ा या नहीं। पर उनका असर जरूर पड़ा होगा। दरअसल हम सविनय अवज्ञानुमा संघर्ष चला रहे हैं। किंतु पिछले आठ वर्षों में हमारे किसान आंदोलन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मसलन, फरवरी में, १९८० में चाकर नामक एक छोटे गांव में जहां महज ५०० किसान और २५ बैलगाड़ियां थीं, प्याज की माकूल कीमतें हासिल करने के लिए मैं धरने पर बैठा था। आज आप देख रही हैं कि हम कहां पहुंच गये हैं।

माया: क्या आप क्रमश: राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं?

जोशी: जनवरी, ८२ में सतारा में हमने अपना राजनीतिक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था कि राजनीति में हमारी रुचि नहीं है। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि कोई, जो भी सरकार सत्ता में आयेगी, वह किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए काम नहीं करेगी। पर यह व्यवस्था किसानों को यदि लाभकारी मूल्य नहीं दे सकती, तो चल नहीं पायेगी। किंतु इसका अर्थ नहीं कि चुनाव आने पर हम घर पर बैठे रहें और इन गिद्धों को घूमने दें। हम चुनावों को इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे आंदोलन मजबूत हों। सतारा का प्रस्ताव इस उद्देश्य को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि हरेक चुनाव के पूर्व हम फैसला करेंगे कि इस चुनाव का इस्तेमाल हमें किस प्रकार करना चाहिए। आठ वर्ष पहले हम ५०० किसानों और २५ बैलगाड़ियों के साथ धरने पर बैठे थे। अब किसान आंदोलन एक राष्ट्र की किस्मत तय कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह शक्ति में परिवर्तन का सूचक है, नीतियों में नहीं।

माया: राजनीतिक होने का यही आरोप समन्वय समिति में लगाया गया था जहां से महेन्द्र सिंह टिकैत उठकर चले गये थे।

जोशी: टिकैत ने यह आरोप नहीं लगाया था कि मैं बदल रहा हूं। उनकी दलील है कि राजनीतिज्ञों के साथ उठना-बैठना भी हमारा चारित्रिक हनन है, क्योंकि वह (टिकैत) दिल्ली के निकट हैं और वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह की तूती बोल रही है, इसलिए टिकैत को राजनीतिक तालमेल का लाभ मिल रहा है। फलस्वरूप टिकैत राजनीतिक तालमेल की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। किंतु शीघ्र ही उनको इसका अहसास हो जाएगा।

> **यदि इस**
> **देश के किसी समुदाय ने**
> **बुद्धिमानी, देशभक्ति, सांस्कृतिक**
> **चेतना और नैतिक सरोकार**
> **दिखाया है, तो वह किसान**
> **समुदाय है।**

माया: आप चुनाव लड़ना क्यों पसंद नहीं करते? क्या इसलिए कि इसके साथ जुड़े पद की जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं?

जोशी: मैं समझता हूं कि इसके लिए मुझसे ज्यादा काबिल लोग मौजूद हैं।

माया: आपके अनुसार विकल्प क्या है? आप न तो चुनाव लड़ना चाहते हैं और न दूसरों के विचारों से सहमत हैं।

जोशी: आज स्थिति ऐसी है कि चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, किसानों को हमेशा आघात ही मिलेगा। हम ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां किसान संगठन पर्याप्त सुदृढ़ हो जायें, इतने सुदृढ़ कि प्रधानमंत्री चाहे जो हो, किंतु वह किसानों के साथ नाइंसाफी करने की हिम्मत न कर सके। पर इसके लिए हममें से किसी को प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। एक लीटर दूध के लिए गाय पालना कोई अक्लमंदी नहीं।

माया: यदि आपका संगठन एक राजनीतिक भूमिका निभाने से मुंह मोड़ता है, तो विधानसभा के मंचों पर आपकी आवाज कैसे बुलंद होगी?

जोशी: हम नहीं चाहते कि विधानसभा के मंचों पर हमारी आवाज सुनी जाये। हमें पता है कि विधानसभा के मंच क्या हैं? राजनीतिक कमीशन एजेंटों की वह बैठक है। जब आप वहां जोरदार भाषण कर रहे होते हैं, तो उस समय अधिकांश लोग काफी हाउस में काफी पीते हैं। मैं नहीं समझता कि विधायी मंचों का अभी कोई महत्व है।

हमें अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने का सही रास्ता पता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमें अपने बाजार से प्रति लीटर दूध का मूल्य ३ रुपए ६० पैसे मिलता है जबकि उपभोक्ता को ६ रुपए देना पड़ता है। इसमें से २ रुपए ४० पैसे सप्लाई-तंत्र को जाता है। हमारा कहना था कि यह २ रुपए ४० पैसे से घटाकर एक रुपए कर देना चाहिए। बहरहाल, मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि वह प्रशासनिक खर्च में कटौती की कोशिश करेंगे तो पूरी सरकार में हड़ताल हो जायेगी। मैंने जवाब दिया, "क्या इसका यह मतलब नहीं कि आप किसानों पर इसलिए अन्याय कर रहे हैं कि वह ऐसी ही धमकी नहीं दे सकते?" यदि अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारी सरकार को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए अभी भी मजबूर कर सकते हैं, तो बहुसंख्यक किसानों को भी अपनी फरियाद के लिए ऐसे ही मार्ग अपनाने पड़ेंगे।

माया: जब किसान ऐसे व्यापक स्तर पर संगठित हो रहे हैं, तो आप हिंसा या अप्रिय घटनाओं को कैसे रोक पायेंगे?

जोशी: मेरा यह मानना है कि जब लोगों की तादाद कम होती है, तभी लोग हिंसक बन जाते हैं। जब हमारी तादाद ज्यादा होती है, तो हमें हिंसक होने की जरूरत ही नहीं होती। वस्तुत:, हिंसा हमारे सारे किये-धरे पर पानी फेर देगी। वैसे तो सरकार हिंसा भड़काने में दिलचस्पी रखती है।

माया: लोगों को आशंका है कि किसानों को संगठित करने में जो भी कामयाब होगा, वह बोतल से जिन बरामद करने जैसा काम करेगा।

जोशी: यदि इस देश के किसी समुदाय ने बुद्धिमानी, देशभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और नैतिक सरोकार दिखाया है, तो वह किसान समुदाय है।

मुझे मालूम है कि कुछ लोग किसानों को बोतल में बंद जिन समझते हैं, क्योंकि उनका भोगविलास और ऐश्वर्य इस जिन के बोतल में बंद होने पर कायम है। किंतु यह भी सच है कि बोतल बंद होने के बावजूद इस जिन ने हमारी नियति को नियंत्रित और राष्ट्र को जीवित कर रखा है और मैं समझता हूं कि राष्ट्र की आस्था-विश्वास तभी जीवंत रहेगा, जब हमारों साल से गुलाम इस जिन को अब आजाद किया जायेगा। ■

मेनका गांधी

शायद मैं अमेठी या कहीं से न लड़ूं

लगभग पांच वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री निवास से साधारण विधवा बहू की तरह निष्कासित मेनका गांधी ने सारे भारत विशेषकर उत्तर भारत में बड़ी-बड़ी सभाएं करके और अपने पति के नाम पर गठित राष्ट्रीय संजय मंच के कई उम्मीदवारों को उपचुनावों में विजय दिलाकर देश की राजनीति में सनसनी पैदा कर दी थी। यहां तक कि एन०टी० रामाराव ने (जो तब खुद भी तेलुगु आत्मसम्मान की वापसी के नारे के साथ सुदूर आंध्र की राजनीति में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे) संजय मंच के उम्मीदवारों के लिए पांच सीटें छोड़ दी थीं। यही नहीं, आपातकाल के प्रतीक संजय गांधी से परहेज के बावजूद अनेक अवसरवादी राजनीतिक दल और नेता मेनका गांधी की लोकप्रियता से लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय संजय मंच से हाथ मिलाने के लिए आतुर दिखायी पड़ रहे थे।

पर ३१ अक्टूबर, १९८४ को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या ने मेनका गांधी और उनके दल राष्ट्रीय संजय मंच की सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। भारतीय जनमानस में अत्याचार की प्रतीक सास की हत्या के बाद पीड़ित-प्रताड़ित विधवा बहू को मिलनेवाली दया-करुणा का स्रोत सूख गया। मृत सास के बेटे ने मां की रक्तरंजित लाश के सहारे लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को धूल चटा दी। मेनका गांधी और उनकी पार्टी को तो हारना ही था, जिनकी सारी राजनीतिक जमापूंजी ही इंदिरा गांधी के विरोध पर आधारित थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जबर्दस्त पराजय के बाद मेनका गांधी का नाम राजनीतिक क्षितिज से विलुप्त हो गया और हताशा में उनके समर्थक विभिन्न दलों में शामिल होने लगे।

वर्ष १९८७ मेनका गांधी के लिए नयी आशा लेकर आया, जब मंच के नंबर दो के नेता अकबर अहमद डम्पी काशीपुर विधानसभाई उपचुनाव में संसदीय कार्यमंत्री डा० अम्मार रिजवी को भारी मतों से हराकर विजयी हुए। काशीपुर नारायण दत्त तिवारी की पारम्परिक सीट रही है और यह माना जाता था कि यहां से तिवारी जी के नाम पर कुत्ता-बिल्ली भी चुनाव जीत सकते हैं, अम्मार रिजवी तो बहुत बड़ी तोप थे। काशीपुर चुनाव ने देश भर में फैले मंच के कार्यकर्ताओं को फिर से जुड़ने का मौका दिया और उनकी ताकत को पहचानकर जनता पार्टी ने मंच को विलय का निमंत्रण देना शुरू कर दिया। पर जार्ज फर्नांडीज तथा कुछ अन्य नेताओं के गैरजिम्मेदाराना बयान से डम्पी भड़क गये और उन्होंने जार्ज को हताश और कुंठित बताते हुए यह घोषणा कर दी कि मंच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखेगा। बाद में लखनऊ में हुए मंच के कार्यकर्ता-सम्मेलन में भी यही फैसला किया गया कि सम्मान को गिरवी रखकर कहीं कोई विलय नहीं किया जायेगा। अलबत्ता, इस मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए मेनका गांधी को अधिकृत कर दिया गया।

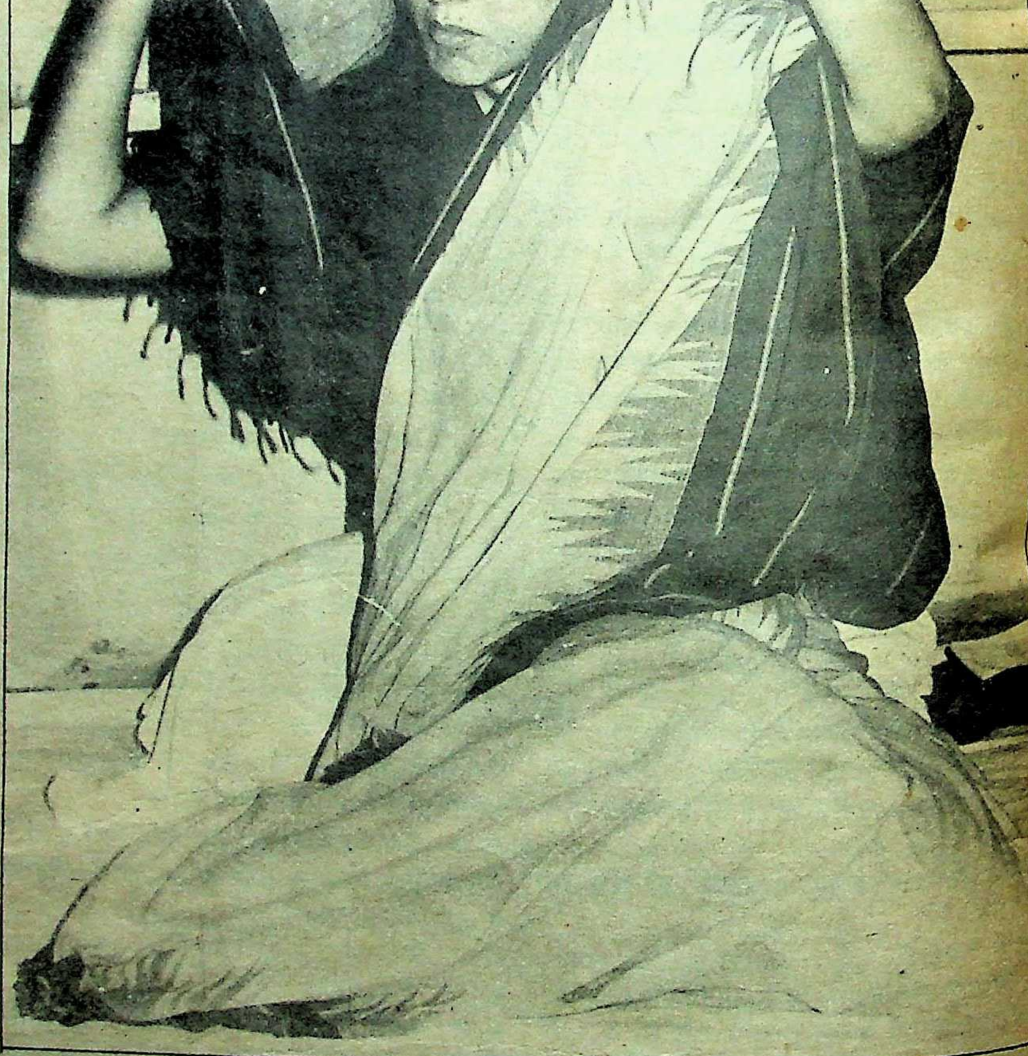

काशीपुर की जीत के बावजूद मेनका गांधी को संभवतः अपने आकर्षण पर पूरा

भरोसा नहीं हो पा रहा था। शायद इसीलिए वह कोई कदम उठाने से हिचकिचाती रहीं। आखिरकार मंच कार्यकर्ताओं के निमंत्रण पर दो महीने पूर्व उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों का दौरा किया। अमेठी ने मेनका को जिस तरह सर माथे पर बिठाया, वह उनके लिए भी आश्चर्यजनक था। बच्चा-बच्चा बोल रहा था, 'राजीव ने रिश्वत खायी है, भ्रष्टाचार मिटाने को बहू मेनका आयी है,' इन नारों के साथ हर जगह उनका जबर्दस्त स्वागत हुआ।

अपने इस स्वागत से उत्साहित होकर मेनका ने अक्तूबर में फिर अमेठी, फैजाबाद बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत और नैनीताल जिलों का दौरा किया और हर जगह बिना किसी प्रयास के उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग जुटे। इन दो सफल दौरों के बाद राजनीतिक दलों का रवैया फिर उनके प्रति बदल गया और आज एक बार फिर उन्हें जनता पार्टी और जनमोर्चा दोनों तरफ से विलय का निमंत्रण मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी मोर्चे के नेता मुलायम सिंह यादव खुद इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि मंच कहीं मोर्चे से संबंध तोड़कर लोकदल-अ से गठबंधन न कर ले।

तीन वर्षों के अंतराल के बाद राजनीतिक मंच पर लौटी मेनका अब पूरी तौर पर एक परिपक्व राजनीतिज्ञ दिखायी पड़ती हैं। मेनका गांधी इन तीन वर्षों में क्या करती रहीं? राजनीति को वह किस नजरिए से देखती हैं? आम लोगों की समस्याओं के बारे में वह क्या सोचती हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर 'माया' ने उनसे लम्बी बातचीत की। पेश हैं, उस बातचीत के चुने हुए अंश:

माया: मेनका जी, पिछले आम चुनावों में पराजय के बाद आप राजनीति से बिलकुल गायब हो गयी थीं। अब जब लौटी हैं, आप क्या नया कहना चाहती हैं?

मेनका: मैं राजनीति से बिलकुल गायब नहीं हुई थी। अलबत्ता, मैंने राजनीतिक मंचों पर जाना बंद कर दिया था। मैं जानती थी कि अभी राजीव को लेकर लोगों में बड़ी आशाएं हैं, मेरी कोई नहीं सुनेगा। बेकार में चीखने-चिल्लाने की जगह मैं कुछ रचनात्मक कामों में लगी थी। विशेष रूप से पढ़ने-लिखने में।

माया: इस दौरान आप क्या करती रहीं, जरा विस्तार से बतायेंगी?

मेनका: इस दौरान मैंने आनलूकर, दिनमान, स्टेट्समैन, इलस्ट्रेटेड वीकली, संडे मेल और प्रोब इंडिया सहित दर्जनों पत्र-पत्रिकाओं में स्तंभ और लेख लिखे। केवल राजनीति पर ही नहीं, शिक्षा, पर्यावरण, बच्चों और महिलाओं की स्थिति से लेकर पेड़-पौधों और जानवरों तक पर। कुछ किताबें भी लिखीं, जिनमें बच्चों की कहानियां और हिन्दुस्तानी फूल-पौधों पर लिखी गयी एक किताब शामिल है। नामों का भी मैं एक संग्रह तैयार कर रही हूं, अभी तक हिन्दुस्तान में यह काम नहीं हुआ है। इस पुस्तक में नामों की उत्पत्ति और उनका अर्थ भी साथ दिया जायेगा। अब तक दस हजार से अधिक नाम मैं इकट्ठे भी कर चुकी हूं।

हम चुप थे, तो सिर्फ इसलिए कि सारा देश चुप था। हम लोग आपस में संपर्क बनाये हुए थे। मुझे पता था कि सही वक्त आने पर हमारी आवाज सुनी जायेगी। जब तीन साल बाद मैं पहली बार अमेठी गयी, तो वहां के लोगों ने पहले से ज्यादा स्वागत किया। देश में और कोई यकीन करे-न-करे, अमेठी के लोगों को तो पता ही है कि वहां चुनावों में भारी धांधली हुई। उस समय लोग कहते थे कि राजीव बगैर धांधली के चुनाव जीत जाते, लेकिन मेरा साफ कहना है कि जो चुनावों में धांधली का सहारा लेता है, वह देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो बंदूक और गोलियों की मदद से वोट लेता है, वह और कुछ भी हो सकता है, लोकतांत्रिक नहीं हो सकता।

माया: पढ़ने-लिखने के अलावा आपने किसी अन्य क्षेत्र में भी समय दिया?

मेनका: और क्या? मैं उपदेशबाजी में यकीन नहीं करती। दिल्ली में मैंने जानवरों के लिए अस्पताल खोला है जो देश का सबसे बड़ा और सुविधा-सम्पन्न अस्पताल है। यहां पालतू पशुओं के अलावा सड़कों पर घूमनेवाले, दुर्घटनाओं में घायल होनेवाले पशुओं का भी इलाज किया जाता है। हम उन्हें अच्छा करके किसी-न-किसी को सौंप देते हैं। कोई नहीं रखता है, तो अपने पास ही रखते हैं। आज भी हमारे पास ७०-८० जानवर हैं।

माया: इस अस्पताल का खर्च आप कैसे चलाती हैं?

मेनका: दरअसल, यह 'रूथ कावेल ट्रस्ट' चलाता है। रूथ कावेल एक आस्ट्रेलियाई महिला थीं जो अपनी सारी सम्पत्ति संजय गांधी के नाम वसीयत कर गयी थीं। हमने उसी पैसे को 'रूथ कावेल ट्रस्ट' बनाकर जमा करा दिया। उसका ब्याज तो मिलता ही है, दूसरे सम्पन्न लोगों के जानवरों के इलाज से भी कुछ पैसा मिल जाता है जिससे अनाथ और बेसहारा जानवरों का इलाज किया जाता है।

माया: आपने इस ट्रस्ट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जानवरों का ही इलाज क्यों रखा? आखिर बहुत से बच्चों और बेसहारों को भी तो इलाज और संरक्षण की जरूरत होती है?

मेनका: बेसहारा बच्चों, अनाथ महिलाओं और बूढ़ों के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं। यह अलग बात है कि उनकी संख्या और बढ़ायी जानी चाहिए, पर जानवरों के लिए कोई कायदे का अस्पताल नहीं है और फिर दुनिया केवल इंसानों के लिए ही तो बनी नहीं है।

माया: एक पांव पशुओं-पक्षियों व किताबों की दुनिया में होने और दूसरा पांव राजनीति में होने से क्या आपको असुविधा नहीं होती?

मेनका: सवाल असुविधा का नहीं उद्देश्यों और इरादों का है। अगर आप दुनिया को पशुओं-पक्षियों-इंसानों सबके लिए खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो राजनीति में हस्तक्षेप करना ही होगा। एक अकेला अदूरदर्शी राजनीतिक फैसला हजारों लोगों को बे-घरबार कर सकता है, समाज, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है।

माया: तीन साल तक निष्क्रिय रहने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए आपने क्या किया?

मेनका: देखिए, हमारे कार्यकर्ता कहीं गये नहीं थे। एक दो गैरमहत्वपूर्ण लोगों को छोड़कर सभी हमारे साथ थे। हम चुप थे, तो सिर्फ इसलिए कि सारा देश चुप था। हम लोग आपस में सम्पर्क बनाये हुए थे। मुझे पता था कि सही वक्त आने पर हमारी आवाज सुनी जायेगी। जब तीन साल बाद मैं पहली बार अमेठी गयी, तो वहां के लोगों ने पहले से ज्यादा स्वागत किया। देश में और कोई यकीन करे न करे, अमेठी के लोगों को तो पता ही है कि वहां चुनावों में भारी धांधली हुई। उस समय लोग कहते थे कि राजीव बगैर धांधली के चुनाव जीत जाते, लेकिन मेरा साफ कहना है कि जो चुनावों में धांधली का सहारा लेता है, वह देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो बंदूक और गोलियों की मदद से वोट लेता है, वह और कुछ भी हो सकता है, लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। लोग आज राजीव को 'करप्ट' (भ्रष्ट) कह रहे हैं, मैं तभी कहती थी कि यह सब करनेवाला सबसे बड़ा 'करप्ट' है। लोगों को अब ही

ANY TOURNAMENTS PLASTICWARE OR THERMOWARE 'BHARAT' REMAINS WINNER

CAPTAIN
Bharat

CHECK UP YOUR LIST AND MAKE SURE THAT 'BHARAT' IS 'CAPTAINING YOUR THIS YEAR DIWALI GIFTS TEAM'!

Bharats' each Item is of
Superb Quality
Sophisticated design
Latest Technology
Attractive Colours
Wide ranges
and above all
Competitive prices.

MANY HAVE TESTED
MANY HAVE TRUSTED

Now the term is yours!

BHARAT
PLASTICWARE

Manufacturers
NATIONAL CELLULOID PRODUCTS
1ST FLOOR, VAKIL IND. ESTATE, WALBHAT ROAD,
GOREGAON (EAST), BOMBAY 400 063 • TEL.: 687027-692421

PRAVEEN GENERAL STORES
LIBERTY GARDEN, OPP. MEHTA INDUSTRIAL ESTATE,
MALAD (WEST), BOMBAY 400 064. TEL: 690393

BHARAT PLASTIC AGENCIES
289, ABDUL REHMAN STREET, 1ST FLOOR,
BOMBAY - 400 003. TEL.: 333852

ADSHOT/NCP/101

अमेठी से राजीव की जीत का भरोसा रहा हो, पर खुद राजीव को नहीं था। नही तो वह धांधली नहीं करने देते। उन्होंने तो अमेठी के लोगों को वोट डालने ही नहीं दिये, यह काम पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से करा लिया।

माया: जो भी हो, राजीव गांधी ने अमेठी का विकास तो बहुत किया है?

मेनका: कैसा विकास! यह अमेठी का विकास नहीं है। राजीव ने गरीब किसानों की जमीनें औने-पौने में पूंजीपतियों-उद्योगपतियों को देकर उन्हें मजबूर बना दिया। इन कारखानों में अमेठी के लोगों को चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली। संजय और मैंने अमेठी के लिए और सपना देखा था, वह था चाहे उद्योग छोटे लगें पर उससे स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिलें। यहां तो बाहर के लोगों ने आकर जमीन, जायदाद, नौकरियों सब पर कब्जा कर लिया। इन कारखानों से अमेठी को चाय की दुकानें खोलने का मौका मिला और क्या? मैंने अपनी सभाओं में लोगों से बार-बार हाथ उठवाकर पूछा कि क्या इन कारखानों में किसी के घर या आसपास के लोगों को नौकरी मिली, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया।

माया: क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में अगली बार लोग राजीव गांधी को चुनाव में हरा देंगे?

मेनका: नहीं। वह चुनाव अभी भी जीत सकते हैं, क्योंकि उन्हें मतदाताओं से तो वोट लेना नहीं है।

माया: इसके बावजूद क्या आप अमेठी से दुबारा चुनाव लड़ना पसंद करेंगी।

मेनका: चुनाव तो शायद मैं अमेठी या कहीं से भी न लड़ूं, पर मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगी।

माया: आनेवाले दिनों में क्या आप मंच का किसी अन्य दल से विलय करने की सोच रही हैं?

मेनका: देखिए विलय के लिए प्रस्ताव तो कई जगह से आ रहे हैं, पर हम इस अकेले मंच के विलय की जगह कई विपक्षी दलों विशेषकर लोकदल-अ और 'ब', जनता, सभी के विलय के पक्ष में हैं। एक मंच के कहीं जा मिलने से क्या फर्क पड़ जायेगा। उत्तर प्रदेश में सात विपक्षी दलों के मेल से बना क्रान्तिकारी मोर्चा इस दिशा में एक अच्छा कदम है, पर लोग सोचते हैं कि टिकट वितरण या नेतृत्व के सवाल पर यह मोर्चा टूट भी सकता है। लोगों की यह आशंका दूर करने के लिए मोर्चे को एक पार्टी में तब्दील करने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें वी०पी० सिंह का जनमोर्चा शामिल हो, तो विपक्ष और मजबूत हो जायेगा।

माया: पर वी०पी० सिंह तो जनमोर्चा को राजनीतिक दल मानते ही नहीं?

मेनका: वह मानें-न-मानें, इससे हकीकत थोड़े ही बदल जायेगी? मैं साड़ी पहने हूं तो मेरे कहने से वह कुर्ता थोड़े हो जायेगा?

माया: तो क्या वी०पी० सिंह को आप स्पष्टवादी नहीं मानतीं?

मेनका: नहीं, नहीं! मेरे कहने का यह आशय नहीं है। वह बहुत अच्छे आदमी हैं, पर उनके 'स्टेटमेंट' परस्पर विरोधी हैं। हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने एक सही मौके पर सरकार की खामियों को उजागर करके 'कैटालिस्ट' (उत्प्रेरक) की भूमिका निभायी है। उन्होंने सरकार के खिलाफ लहर बनायी, पर हमारी समझ में यह नहीं आता कि वह जाना कहां चाहते हैं अभी तक उन्होंने सिर्फ विरोध किया है, यहां तक कि उस आपातकाल का भी विरोध किया, जिसमें वह केन्द्र सरकार में मंत्री थे, पर लोग उनसे रास्ता पूछ रहे हैं।

राजीव ने गरीब किसानों की जमीनें औने-पौने में पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को देकर उन्हें मजबूर बना दिया। इन कारखानों में अमेठी के लोगों को चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली। संजय और मैंने अमेठी के लिए और सपना देखा था, वह था चाहे उद्योग छोटे लगें, पर उससे स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिलें। यहां तो बाहर के लोगों ने आकर जमीन, जायदाद, नौकरियों सब पर कब्जा कर लिया। इन कारखानों से अमेठी को चाय की दुकानें खोलने का मौका मिला और क्या? मैंने अपनी सभाओं में लोगों से बार-बार हाथ उठवाकर पूछा कि क्या इन कारखानों में किसी के घर या आसपास के लोगों को नौकरी मिली, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया।

माया: राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि आप अन्य लोगों की अपेक्षा रामकृष्ण हेगड़े को अधिक महत्व देती हैं।

मेनका: यह सच नहीं है। मैं सभी लोगों से मिलती हूं। हेगड़े से ज्यादा तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष से मिली हूं। पर यह जरूर मानती हूं कि हेगड़े देश के ईमानदार नेताओं में से हैं।

माया: आज से कुछ महीने पहले मंच और जनता पार्टी के विलय की काफी चर्चा थी। पर बाद में सब टांय-टांय फिस्स क्यों हो गया?

मेनका: जनता पार्टी ने ही विलय का प्रस्ताव किया था, पर बाद में उन्हीं के कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसलिए हमने आगे कदम बढ़ाना उचित नहीं समझा।

माया: जनता पार्टी में मंच के विलय का विरोध जार्ज फर्नांडीज ने किया था। उनका कहना था कि मंच एक सिद्धांतविहीन अवसरवादी संगठन है।

मेनका: मंच को सिद्धान्तविहीन और अवसरवादी कहना मूर्खता है। मंच किसी दक्षिण या वाम पंथ में यकीन नहीं करता। मेरे ख्याल से हमारी विचारधारा दूसरों मे ज्यादा आशावादी और व्यावहारिक है। किताबों में लिखे सिद्धांतों और दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर देश को चलाने की उम्मीद लिए बहुत से लोग आज भी लाठी से पानी पीटते ही नजर आते हैं।

माया: आपने अपनी नीतियां कभी स्पष्ट करने की कोशिश भी तो नहीं की। आपकी मुख्य बात हमेशा इंदिरा और राजीव-विरोध तक ही सीमित रही?

मेनका: ऐसा कहना गलत है। हमारी पार्टी का घोषणा-पत्र और समय-समय पर पारित किये गये प्रस्ताव पढ़ लीजिए। हमने हमेशा बड़े-बड़े उद्योगों की जगह गांधीजी और चरण सिंह की तरह लघु और कुटीर उद्योगों की हिमायत की है जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। किताबी शिक्षा की जगह व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षा की मांग हम हमेशा से उठाते रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में सामूहिक खेती पर हमारा जोर रहा है। परिवार नियोजन अपनाने वालों को शिक्षा-रोजगार सभी कामों में प्राथमिकता दिये जाने की हमारी मांग रही है। राष्ट्रीयकरण के जरिए सभी उद्योगों विशेषकर बीमार उद्योगों के अधिग्रहण की हमने हमेशा आलोचना की है। रक्षा बजट में वृद्धि और पड़ोसियों से दादागिरी के हम विरोधी हैं। आखिर क्या कमी है, हमारी नीतियों में। राजीव अगर इन्हीं मोटी-मोटी नीतियों को लागू कर दें, तो देश कहां-से-कहां पहुंच जाये। पर हर मामले में वह उलटा कर रहे हैं।

माया: अगर राजीव इन नीतियों को लागू कर दें, तो क्या आप इंका में लौट जायेंगी।

मेनका: यह एक ऐसा काल्पनिक सवाल है, जिसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।

माया: अब आपका भावी कार्यक्रम क्या है?

मेनका: फिलहाल तो मैं एक से चार दिसम्बर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा करने जा रही हूं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जायेगा।

माया: अकेले उत्तर प्रदेश पर इतना ध्यान केंद्रित करने की कोई खास वजह?

मेनका: रावणरूपी कांग्रेस की नाभि उत्तर प्रदेश ही है। यहीं चोट करने पर वह मरेगा।

—लखनऊ ब्यूरो

बोफोर्स दलाली प्रकरण

नया रहस्योद्घाटन

अभी तक यही बात सामने आयी थी कि बोफोर्स की दलाली में देश के ३० करोड़ रुपयों पर हाथ साफ हुआ है। लेकिन अब नया रहस्य खुला है, जिससे ज्ञात होता है कि मामला ६०० करोड़ रुपए हजम करने का था। यह नया मामला क्या है और वे नये लोग कौन हैं, जिनके नाम बोफोर्स के नये घोटाले से जुड़े हैं?

बोफोर्स के मामले से अनेक लोगों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। इनमें हिंदुजा, चड्ढा, बच्चन, प्रधानमंत्री के इतालवी रिश्तेदार और स्वयं प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। इससे न केवल देश की गरिमा पर चोट पहुंची है, बल्कि देश को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। हां, देश को बदनामी से बचाया जा सकता था, बशर्ते सरकार अपने मंत्रियों और कूटनीतिज्ञों को परस्पर विरोधी बयान देने की छूट न देती और न बोफोर्स कंपनी को यह अधिकार देती कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री और एक सांसद को चरित्र का प्रमाण-पत्र दे।

६०० करोड़ रुपयों पर नजर: बहरहाल अभी तक लोगों के ध्यान में यही बात जमी हुई है कि बोफोर्स की दलाली में केवल ग्यारह कंपनियों के हाथ सने हैं। इन कंपनियों की सूची 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुई थी। लेकिन 'माया' को पता चला है कि बोफोर्स कांड में लिप्त लोगों की संख्या ज्यादा है। यह भी सही नहीं है कि इस कांड में केवल ३० करोड़ रुपए ही इधर-से-उधर हुए हैं। सूत्रों का अनुमान है कि देश से ६०० करोड़ से ज्यादा रुपए देश से पार करने की योजना बनी थी।

इस सारे घपले के प्रारंभिक सूत्र को तलाशने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। यह १९८५ की बात है कि भारत को १५५ एम एम होवित्जर तोपें बेचने वाली चार कंपनियां मैदान में थीं: आस्ट्रियन जीसी ४५, ब्रिटिश-जर्मन-इटेलियन एफएच-७०, फ्रेंच जियाट १५५ टीआर और स्वीडिश बोफोर्स एफएच-७७। आखिर में फ्रेंच जियाट १५५ टीआर और स्वीडन की बोफोर्स कंपनी प्रतियोगिता में ठहरीं। फ्रांस की तोपों का जब परीक्षण हुआ, तो उन्होंने २९ किलोमीटर तक मार की, जबकि निर्धारित दूरी ३० किलोमीटर थी। स्वीडन की तोपों के गोले तो मात्र १५ किलोमीटर तक ही पहुंच सके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि स्वीडन की तोपों को निर्णायकों ने प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया—और इसी कारण लोगों को शक हुआ कि कुछ दाल में काला है। स्वीड़न को पोखरण क्षेत्र में अपनी मारक-शक्ति दिखाने के लिए फिर मौका दिया गया। लेकिन इस बार भी गोले २१ किलोमीटर तक ही पहुंच सके। हिसाब से इस परीक्षण के बाद बोफोर्स की तोपों का विचार छोड़ देना चाहिए था।

रियायत: लेकिन इस मौके पर बोफोर्स कंपनी ने वायदा किया कि यदि भारत सरकार उससे अनुबंध करे, तो वह ३० किलोमीटर की मार करने की शक्ति पैदा करने के लिए वांछित सुधार कर सकती है। फ्रांस की कंपनी ने भी कहा कि वह भी सुधार कर सकती है और उसने दावा किया कि उसकी तोपें सुधार के बाद ३३ किलोमीटर तक मार कर सकेंगी। उन्होंने तो यह भी कहा कि उनकी तोपें इसलिए भी बेहतर होंगी, क्योंकि वे १२ से १५ सेकिंड में तीन चक्र गोले दाग सकेंगी। एक महत्वपूर्ण

सूचना फ्रांस की कंपनी ने और दी। उसका कहना था कि उनकी तोपें पहले से युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता सिद्ध कर चुकी हैं, क्योंकि फ्रांस की सेना इन तोपों का इस्तेमाल कर रही है। ज़ानकार सूत्रों का कहना है कि स्वीडन ने तोपों के जिस मॉडल का प्रस्ताव भारत के सामने रखा था, उस मॉडल को स्वीडन की फौजें इस्तेमाल में नहीं ला रही हैं। इस प्रकार हालात फ्रांस के पक्ष में थे। लेकिन बताया जाता है कि २३ मार्च, १९८६ की शाम को देर गये प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलायी और समिति ने तुरंत बोफोर्स की तोपों के लिए की गयी सरकार की सिफारिश पर अपनी मोहर लगा दी। बोफोर्स के साथ अनुबंध हो गया। सूत्रों के अनुसार बोफोर्स का अंतिम प्रस्ताव फ्रांस के प्रस्ताव से ३० करोड़ रुपए सस्ता था।

अनेक सवाल: जिन परिस्थितियों में यह सौदा तय हुआ, उनको देखते हुए अनेक सवाल खड़े होते हैं। फैसला इतना अचानक कैसे हुआ? कीमत कैसे तय हुई? बोफोर्स ने सारे अनुबंध के लिए १,९०० करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये संकेत दिये थे कि सौदा १००० करोड़ तक पट सकता है। जिस १४०० करोड़ रुपए की कीमत का मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमोदन किया, उसे किसने तय किया था?

ये ही कुछ बातें हैं, जिनके कारण तरह-तरह के शक-शुबहे हुए हैं। बताया जाता है कुछ भारतीय दलालों ने बोफोर्स तक यह बात पहुंचायी कि यदि बोफोर्स अनुबंध का बीजक ४०० करोड़ रुपए बढ़ाकर (ओवरइनवोइसिंग) पेश करने के लिए सहमत हो जाये, तो उसे अनुबंध मिल सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि बोफोर्स १००० करोड़ रुपए ले और १४०० करोड़ रुपए का बिल बना कर दे, तो काम बन सकता है। मौका बढ़िया था, इसलिए बोफोर्स ने और धन ऐंठने की तरकीब सोची। उसने पेशकश की किं उसे ३० किलोमीटर से अधिक मार करने के लिए गोला बारूद में सुधार की खातिर २०० करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि और दी जानी चाहिए। इसका मतलब था कि अब ४०० करोड़ रुपए के बजाय केवल २०० करोड़ रुपए पर ही हाथ साफ किया जा सकता था। उस राशि से ज्यादा अनुबंध के लिए दिया भी नहीं जा सकता था जो राशि फ्रांस ने मांगी थी। वह राशि लगभग १,४५० करोड़ रुपए थी।

नयी तरकीब: इसी समय भारतीय निर्णयकर्ताओं ने बदले के व्यापार (काउंटर ट्रेड) का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में यह बात थी कि बोफोर्स को भारत से १२,०० करोड़ रुपए का माल भेजा जायेगा, लेकिन बिल ८०० करोड़ रुपए का दिया जायेगा। इस प्रकार ८०० करोड़ रुपए भारत को वापस मिल जायेंगे, लेकिन बाकी के बचे ४०० करोड़ रुपए अवैध रूप से किसी विदेशी बैंक में जमा कर दिये जायेंगे। बोफोर्स को एक और 'लालच' दिया कि उससे तोप प्रणाली के सह उत्पादन का २००० करोड़ रुपए का एक अनुबंध और कर लिया जायेगा। २३ मार्च, १९८६ को बोफोर्स कंपनी भारतीय शर्तों पर रजामंद हो गयी। उसी शाम को भारत ने इसका अनुमोदन कर दिया और अगले दिन करार पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो गये।

थापर-त्रेहान का प्रवेश: ठीक इसी समय कुछ नये खिलाड़ी मैदान में उतरे, जिनमें उद्योगपति एल०एम० थापर और वी०एम० त्रेहान का नाम भी शामिल है। राजीव गांधी के नजदीकी मित्र और भारत के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक थापर काफी अरसे से हथियारों के सौदों में हैं। थापर भारत में लगभग ४२ ऐसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रतिरक्षा से जुड़े उपकरणों का व्यापार करती हैं, इनमें 'साबस्केनिया ए बी' भी है जो १५५-एम०एम०, इ०एच०-७७ बी होवित्जर तोपों के लिए ट्रकों की आपूर्ति करती है। विपक्षी नेताओं के अनसार प्रधानमंत्री से दोस्ती और दून स्कूल में साथ रहने के कारण बोफोर्स में उनकी दिलचस्पी और बढ़ी। प्रधानमंत्री और थापर की निकटता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उड़ान अवधि की शर्त पूरी करने की खातिर थापर के ही निजी विमान का इस्तेमाल किया था।

समझा जाता है कि प्रधानमंत्री के निकटस्थ लोगों ने सुझाव दिया था कि बोफोर्स से बदले के व्यापार का काम थापर को सौंपा जाये। थापर उस समय 'फेरा' (विदेशी मुद्रा नियमन कानून) से परेशान थे और उन्हें एक 'काबिल' व्यक्ति की जरूरत थी। इसके लिए उनकी नजर 'मेकस्टर ग्रुप' के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र मोहन त्रेहान पर पड़ी जो उनके कृपा पात्र भी थे और भरोसेमंद भी।

त्रेहान अपने बलबूते पर व्यवसायी बने थे। एम०के० जाजोदिया की एक कंपनी विलियम जैक्स प्रा०लि० में भी उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम किया था। कड़ी मेहनत, विलक्षण बुद्धि, शिष्टता और हर मुश्किल काम को निपटाने की क्षमता के कारण उन्होंने जाजोदिया के दिल में जगह बना ली थी। जाजोदिया ने ही बाद में उनका परिचय हथियार व्यापार जगत और उसमें लगी थापर जैसी हस्तियों से कराया। इसके बाद त्रेहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

बहुत जल्दी ही त्रेहान अमरीकी मशीन टूल्स कंपनी (स्नैप आन टूल्स) के भारतीय प्रतिनिधि बन गये। १९७१ में उन्होंने मेहरा, खन्ना और शर्मा

विरोधाभास

विरोधाभास-१: ७ सितंबर को पूर्व सांसद अमिताभ बच्चन ने एक पत्रकार सम्मेलन में बोफोर्स कंपनी के अध्यक्ष मोरबर्ग के उस तार को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्हें 'क्लीन' साबित किया गया था। तार का मजमून कुछ इस तरह था, "आप और आपके भाई अजिताभ बच्चन, बोफोर्स द्वारा भारत को बेची गयीं एफ०एच०-७७ होवित्जर तोपों या अन्य किसी भी सौदे में शामिल नहीं थे। यह भी पक्की तौर पर कहा जा रहा है कि इस सौदे में आपको या आपके भाई को कोई रकम नहीं दी गयी है।"

दूसरी तरफ स्वीडन में भारतीय राजदूत भूपतराय ओझा ने ५ सितंबर को कहा था कि "बोफोर्स (कंपनी) ने कई बार हमें गुमराह किया है और जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि जो वह कह रही है, सच है, तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता।"

विरोधाभास-२: जुलाई में सरकार ने कहा कि उसने बोफोर्स द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तर्क दिया था, "इससे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह कुछ बताने को तैयार नहीं है। और ऐसे लोगों से बात करने का भी क्या फायदा जो बात ही नहीं करना चाहते।"

रक्षा राज्यमंत्री शिवराज पाटिल ने बाद में सफाई दी, "बोफोर्स के उपाध्यक्ष बोर्टिल ब्रेडिन आयोग को दलाली खाने वालों के नाम मौखिक रूप से बताना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि वह ये नाम लिखित रूप में दें, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं हैं।"

और इसी सरकार ने सितंबर में बोफोर्स कंपनी के अध्यक्ष पीटर ओ मोरबर्ग के दिल्ली आगमन पर न केवल पलक पांवड़े बिछाये, बल्कि उन्हें यह भी समझाया गया कि संयुक्त संसदीय समिति के सामने क्या जवाब दें।

विरोधाभास-३: अगस्त में राजीव सरकार ने वी०पी० सिंह सहित सभी विपक्षी नेताओं की इसलिए आलोचना की थी कि वे बोफोर्स प्रकरण में दलाली खाने वालों के नामों का पता लगाने के लिए स्वीडन सरकार की मदद लेने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने कई बार यह कहकर इन विपक्षी नेताओं की देशभक्ति पर शंका जाहिर की थी कि "यह देश के सम्मान के साथ समझौता होगा और देश की एकता खतरे में पड़ जायेगी। या कोई और देश यह जांच करेगा, तो भारत उपहास का केंद्र बन जायेगा।"

बहरहाल, यह ध्यान देने योग्य बात है कि 'बोफोर्स प्रकरण' की जांच की शुरुआत से ही भारत सरकार विदेशी एजेंसी की मदद ले रही है। भारत सरकार की प्रार्थना पर ही स्वीडन सरकार ने 'स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो' से जांच शुरू करवायी थी।

साक्षात्कार/वीरेन्द्र मोहन त्रेहान

स्वीडन अभी कुछ नहीं गया

एक सेल्समैन की हैसियत से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले 'मेकस्टर' कंपनी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक वी०एम० त्रेहान सफलता का एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। 'माया' से बातचीत करते हुए त्रेहान कहते हैं, "शायद मेरी इसी सफलता से लोग जलते हैं और मुझे तथा मेरी कंपनियों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। दुर्भाग्यवश कुछ पत्रकार भी इसमें उनकी मदद कर रहे हैं।" प्रस्तुत हैं, 'माया' से उनकी बातचीत के कुछ अंश :

माया: क्या आपने कभी एम०के० जाजोदिया की कंपनी विलियम जैक्स प्रा०लि० में काम किया था?

त्रेहान: मैंने उस कंपनी में १९६१ से १९६७ तक काम किया था। उस समय वह ब्रिटिश कंपनी थी। १९७०-७१ में इस कंपनी के मालिक जाजोदिया हो गये।

माया: कंपनी छोड़ने के बाद जाजोदिया से आपके कैसे संबंध थे?

त्रेहान: मैं ऐसे लोगों से संबंध रखना पसंद नहीं करता।

माया: क्या आप एल०एम० थापर को जानते हैं? ऐसा समझा जाता है कि आप उनके करीबी हैं?

त्रेहान: मैं किसी भी बड़े आदमी को नहीं जानता। बहुत कम बड़े उद्योगपतियों से मेरा परिचय है। कई लोगों ने मुझे थापर से मिलने को कहा, क्योंकि मैं फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ) और एसोकेम (एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स) का सदस्य चुना गया था। इन संस्थाओं से संबंधित दिक्कतों के बारे में मुझे थापर से मिलने को कहा गया था। वह 'उत्तर भारतीय' हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं छोटा आदमी हूं और मुझे छोटा ही रहने दो। निश्चित रूप से वह उत्तर भारत के एक बड़े उद्योगपति हैं और उनसे मिलकर मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था। लेकिन यह अलग बात है। एक बार विमान यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात जे०आर०डी० टाटा से हुई। वह काफी सुखद यात्रा थी। मुझे विमान मे १० मिनट उनके बगल की सीट में बैठने का अवसर मिला और उनसे बात करने में मुझे बहुत आनंद मिला। बड़े लोगों से मुलाकात में मुझे हमेशा आनंद आता है, लेकिन उनसे मिलने का कोई मौका तो मिले। मैं मात्र मुलाकात के लिए किसी के पीछे दौड़ना पसंद नहीं करता।

माया: इन दिनों आपका प्रमुख धंधा क्या है?

त्रेहान: हमारी सैकड़ों भारतीय और विदेशी एजेंसियां हैं, जो निर्माण के उपकरण, पेट्रो-रासायनिक, उच्च इंजीनियरिंग के उपकरणों और अन्य यंत्रों की खरीद-फरोख्त करती है।

माया: क्या आपने बोफोर्स से एस०टी०सी० के साथ अकेले कोई 'बदले के व्यापार' (काउंटर ट्रेड) का समझौता किया था?

त्रेहान: एस०टी०सी० के साथ ऐसा समझौता किया था। मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया था। 'एसोकेम' के सदस्य के तौर पर हम विभिन्न बैठकों में मिलते रहते थे। इन्ही बैठकों के दौरान एक एस०टी०सी० अधिकारी ने हमें बताया कि स्वीडन की पार्टी का एक व्यापारिक अधिकारी यहां है। यह १९८७ के शुरुआत की बात है। उन्होंने (एस०टी०सी० के अधिकारी ने) मुझे उनसे मिलवाया। उस स्वीडन अधिकारी ने मुझसे कहा, "त्रेहान तुम हमेशा स्वीडन को सामान निर्यात करने की बात करते हो। इसके लिए बिलकुल उपयुक्त समय है।" अतः मैंने साथियों से बोफोर्स के लोगों से मिलने को कहा। वे उनसे मिले और बातचीत शुरू हो गयी। दो तीन महीनों में हमारे बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत हमें विभिन्न देशों को सामान सप्लाई करना था। बोफोर्स को इसमें हमारी मदद करनी थी और इससे उसका खुद का भी व्यापार बढ़ता। यहां तक कि वह हमें कुल निर्यात पर कमीशन देने को भी तैयार थी, लेकिन बंबई में एस०टी०सी० अधिकारियों के सामने इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दो महीनों के बाद कुछ लोगों ने लिखा कि बोफोर्स प्रकरण में मेकस्टर भी शामिल है। हम इसे पसंद नहीं करते।

माया: कौन-सी चीजें निर्यात करनी थीं?

त्रेहान: केवल भगवान जानता है, हमने एक पैसे का भी व्यापार नहीं किया फिर।

माया: प्रतिव्यापार (काउंटर ट्रेड) के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए?

त्रेहान: १९८७ के अप्रैल-मई में। हम उनसे (स्वीडन की फर्म के प्रतिनिधियों से) जनवरी-फरवरी में 'इंटरनेशनल चैंबर आफ कामर्स कांफ्रेंस, में मिले थे और अप्रैल-मई में समझौते पर दस्तखत हुए। समझौते की प्रतिलिपि पुलिस, एस०टी०सी० के पास और हमारे कार्यालय में है।

माया: क्या बोफोर्स के प्रतिनिधियों के पास भी प्रतिलिपि है?

त्रेहान: हां, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि यह निर्यात से जुड़े लोगों के लिए है। कोई श्री जानसन थे जो विदेश में भारतीय निर्यात के काम देखते हैं।

माया: लेकिन जैसा कि आपने कहा, इस मामले में पहल एस०टी०सी० के लोगों ने की थी।

त्रेहान: हां, यह स्वाभाविक है। एस०टी०सी० के लोग इसके अंग हैं। सारा निर्यात तो एस०टी०सी० की मार्फत ही होना था। मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अन्य लोगों के साथ (समझौता पर) हस्ताक्षर किये हैं।

माया: क्या आपको अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी है?

त्रेहान: मुझे कुछ पता नहीं।

माया: इस सिलसिले में आपकी कभी विन चड्ढा से मुलाकात हुई, क्योंकि वही बोफोर्स के वैध प्रतिनिधि थे?

त्रेहान: मैंने आपसें कहा है कि मैं किसी बड़े व्यक्ति को नहीं जानता। मैं सदा अपनीं दुनिया तक सीमित रहता हूं। अभी हमारी कंपनी नयी है और हमें काफी कुछ करना है। हम सुबह पांच बजे से रात के ग्यारह बजे तक व्यस्त रहते हैं और जितना काम हो सकता है, उतना करने की कोशिश करते हैं। हमने अन्य चीजों के व्यापार को भी हाथ में लिया है। केवल व्यापार, निर्माण ही नहीं, हम ट्रैवेल एजेंसी का काम भी करते हैं।

माया: क्या आपने कभी विदेशी कंपनी के भारत स्थित एजेंट के रूप में भी काम किया है?

त्रेहान: देखिए, हमारी कंपनी एक प्रतिनिधि है,

इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं भी एक प्रतिनिधि हूं और इसी प्रकार अन्य कर्मचारियों को भी मान सकते हैं।

माया: लेकिन क्या आपकी कोई कंपनी सैन्य उपकरणों की भी आपूर्ति करती है।

त्रेहान: हमें प्रतिरक्षा से कुछ लेना-देना नहीं। हमारे सभी उपकरण नागरिक उपयोगिता के हैं। मुझे धन का भी कोई लालच नहीं।

माया: लेकिन क्या सच नहीं है कि अनेक सेवा निवृत्त सेनाधिकारी भी आपके काम से जुड़े हैं?

त्रेहान: यह सच है। १९७३ में हमारे अध्यक्ष एयर मार्शल चटर्जी थे। देखिए, सुरक्षा से केवल अस्त्र-शस्त्रों का ही ताल्लुक नहीं है। फौजों को अनेक नागरिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है।

माया: सही बात है। मेजर जनरल बिष्ट और मेजर मल्होत्रा भी आपके यहां काम करते हैं।

त्रेहान: नहीं, नहीं। मे०ज० बिष्ट 'फाउंडेशन फार एमिटी ऐंड सालिडेरिटी' के लिए काम करते हैं। यह अलग कंपनी है। बेशक कुछ मामलों में मेरा भी उससे संबंध है। जनरल बख्शी ने भी हमारे साथ दो साल तक काम किया है। जब ये फौजी अफसर सेवानिवृत्त होते हैं, तो हमें उनकी प्रतिभा का फायदा उठाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने ऐसा करके कोई अजीब कार्य किया है। यहां तक कि चौकीदार के लिएं भी आपको किसी सैनिक की तलाश रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी पत्रिका 'टेलीमेटिक्स' से ईर्ष्या करते हैं। इस मामले में उन्होंने कई तरह की बातें लिखी हैं। इसके संपादकीय के सलाहकार मंडल में सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं। लेकिन संपादकीय सलाहकार बोर्ड का काम सलाह देना है, यह कोई नौकरी नहीं है। लोगों के ईर्ष्यालु होने के दो कारण हो सकते हैं: एक तो वे प्रतियोगिता से डरते हैं। वे यह पसंद नहीं करते कि कोई व्यक्ति नये प्रकाशन संस्थान को खड़ा करे। हमने तय किया है कि हम एक प्रकाशन संस्थान खड़ा करें। 'टेलीमेटिक्स' हमारी पहली पत्रिका है। यह व्यावसायिक और तकनीकी मामलों की पत्रिका है और भगवान ने चाहा, तो हम और निकालेंगे। हमने तो डा० संजीवी राव (पूर्व मंत्री) से भी अनुरोध किया था कि वह हमारी मदद करें, यद्यपि उनके पास कोई पद नहीं है। वह विवेकशील व्यक्ति हैं। 'संडे आब्जर्वर' के एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिखा है कि मेरे संबंध सैम पित्रोदा और दूसरों से हैं। सैम हमारे दोस्त हैं और हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं। वह जानते हैं कि हम राष्ट्रीय हित में काम कर रहें हैं—यह बात दूसरी है कि हम विदेशी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

माया: किस राष्ट्रीय हित के लिए?

त्रेहान: घरेलू विकास संबंधी राष्ट्रीय हित के लिए।

माया: हाल में आपने एमिटी ऐंड सालिडेरिटी आर्गेनाइजेशन (एसरो) की स्थापना की है। इसकी क्या भूमिका है? क्या आप इसका उपयोग महत्वपूर्ण लोगों और निर्णयकर्ताओं से संबंध बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

त्रेहान: यह बिलकुल गलत है। 'एसरो' के द्वारा विशिष्ट लोगों से मिलने वाला मैं अकेला नहीं होऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से पक्षपात करने को नहीं कहा। वास्तव में, मेरे मित्र मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं 'व्यापारी' क्यों नहीं हूं? एसरो एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसके लिए मैंने काफी धन और समय खर्च किया है। इस अर्थ में मैंने कुछ समर्पित ही किया है, इससे मुझे महसूस होता है कि मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहा हूं।

माया: क्या यह सच है कि आपके पुत्र संजय ने इसी साल स्वीडन की यात्रा की थी और उनके बाद आपने भी?

त्रेहान: हां, जहां तक मेरा सवाल है। मैं अपने कई उत्पादों के निर्यात के सिलसिले में इस साल कई बार स्वीडन गया हूं।

माया: वहां आप किन कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं?

त्रेहान: कई के साथ। निर्माण से संबंधित लिंडर एलीमेंट्स से, डायनापैक कंपनी से कंडक्टरं संबंधी लेन-देन है। इस समय संजय कुछ इलेक्ट्रानिक सामान बेचने की बातचीत करने लिए स्वीडन गया है। लेकिन सब कुछ अभी बातचीत के स्तर पर ही है। हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 'मेकस्टर' एक छोटी निर्यात कंपनी है, जो एक करोड़ तक का भी व्यापार करती है। हमें अपने उत्पाद के लिए बाजार तलाशना पड़ता है।

माया: आप कौन-सी चीजें निर्यात कर रहे हैं?

त्रेहान: सजावटी कपड़े, ऊन, टेक्सटाइल्स तथा कुछ और चीजें, लेकिन स्वीडन अभी कुछ भी नहीं भेजा गया। अभी हमने जांच-परख के अलावा कुछ नहीं किया है। यह तो लड़की से बात करने जैसा है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उसके साथ सो रहे हैं। निश्चित रूप से बोफोर्स कांड के बाद मेरी स्वीडन यात्रा पर लोगों का शक स्वाभाविक है। लेकिन यह गलत भी है। आखिरकार हम निर्यात के व्यापार में हैं।

माया: क्या एस०टी०सी० के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मूलजी ने आपको निर्यात-व्यापार में सहयोग दिया था?

त्रेहान: एस०टी०सी० में मैं किसी को नहीं जानता। कुछ साल पहले मेरा परिचय कुछ लोगों से था, लेकिन अब बिलकुल नहीं है।

माया: लेकिन मूलजी एस०टी०सी० के पूर्व अध्यक्ष थे?

त्रेहान: मैं उनके संपर्क में कभी नहीं आया।

—प्रकाश नंदा

उपनामधारी तीन महानुभावों के सहयोग से एक निजी कंपनी 'मेकस्टर' स्थापित की। बाद में त्रेहान की महत्वाकांक्षाओं के कारण तीनों सहयोगी अलग-अलग हो गये। थापर और अन्य बड़ी हस्तियों की कृपा से 'मेकस्टर' ऐसे उपकरणों का उत्पादन और व्यापार करने लगी जो खतरनाक जगहों में निरापद सिद्ध हो सकें। मेकस्टर ने निर्यात का काम भी हाथ में लिया, जिसकी बदौलत १९८६ में त्रेहान ने अपनी कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर ४० करोड़ रुपए घोषित किया। १९८३ में तो जैसे त्रेहान को सोने की खदान ही हाथ लग गयी थी। उस समय फ्रांसीसी दूर संचार साधनों की कंपनी एलेक्टेल थामसन ने उसे भारत में अपना एकमात्र प्रतिनिधि बना लिया था। त्रेहान को दूरसंचार के क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एलेक्टेल थामसन ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया और कंपनी को भारत से अरबों का ठेका भी मिल गया। इससे त्रेहान की पहुंच का अंदाजा मिलता है। अब त्रेहान अन्य बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से नाता जोड़ने की सोच रहे हैं। इन कंपनियों में केंडल पालीकेन, गार्डनर डेनवेर (अमरीका), स्वेडबोवर (स्वीडन), एफ०बी०एम० (इटली) और वर्थ (पश्चिम जर्मनी शामिल हैं।

STATE TRADING CORPORATION

संदिग्ध भूमिका: एस०टी०सी० भवन

सूत्रों के अनुसार जब थापर ने त्रेहान से इस बदले के व्यापार (काउंटर ट्रेड) का सुझाव दिया, तो वह उछल पड़े। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन 'मेकस्टर्स' के विदेशी सहयोग की देखरेख करने वाले त्रेहान के ज्येष्ठ पुत्र संजय त्रेहान ने अप्रैल में स्वीडन की यात्रा की थी। बताया जाता है कि कुछ सप्ताह में राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) के अधिकारियों की उपस्थिति में वहां एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इस करार के तहत मेकस्टर को २ प्रतिशत और एस०टी०सी० को ८.५ प्रतिशत कमीशन मिलना तय हुआ। त्रेहान को केवल एक मध्यस्थ और महाजन की भूमिका निभानी थी। उनको एक भारतीय कंपनी से माल खरीदना या

नेशनल इंश्योरेंस की फाइल से

एक फैसला, सही समय का...

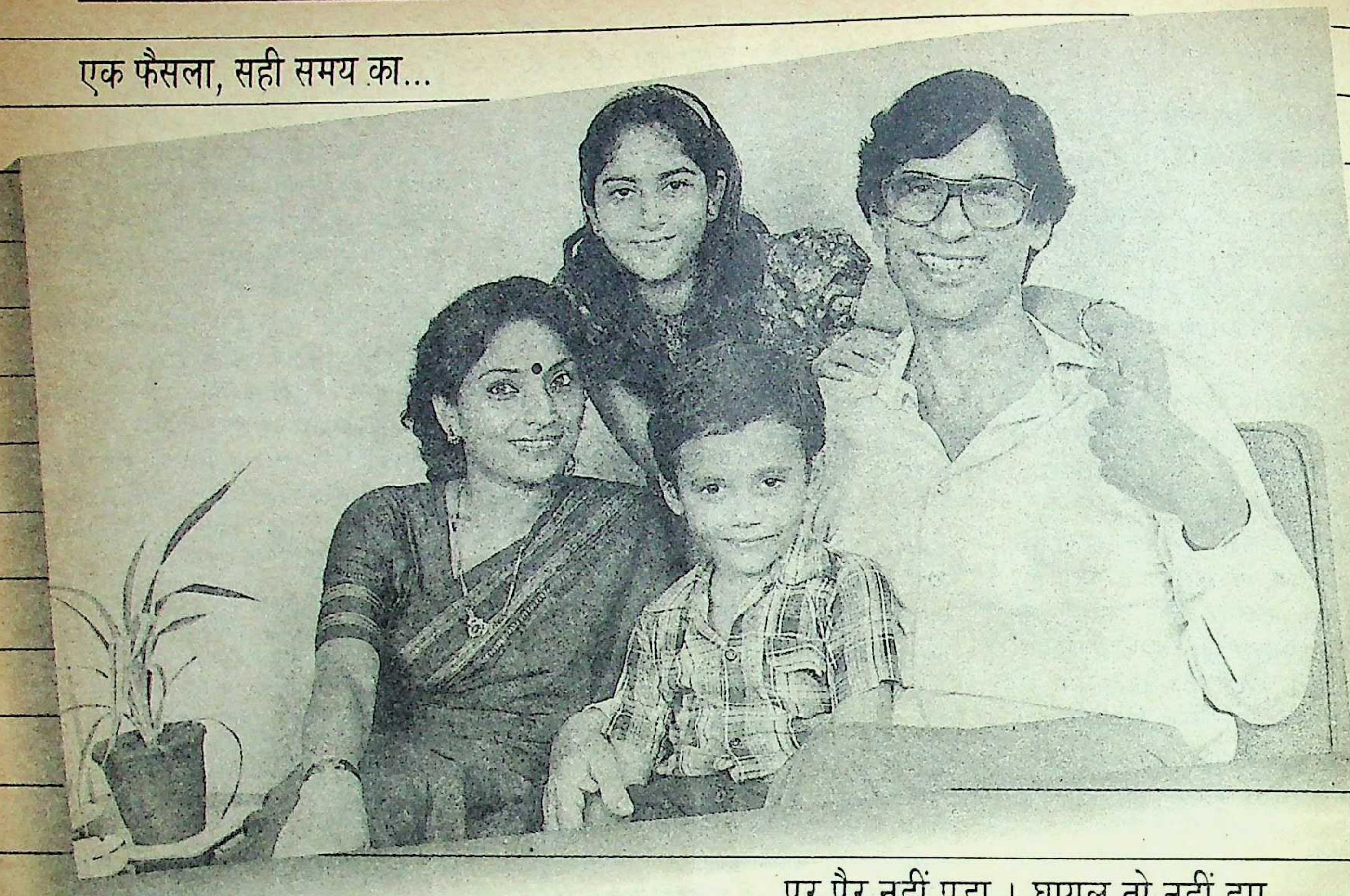

अनिल भार्गव, उम्र ४० वर्ष,
माया के पति, रंजू और मीनू के पिता,
स्नेहशील जीविकोपार्जक,
परिवार का एकमात्र सहारा,
झपट कर चलने वाला, एक बार में
दो दो सीढ़ियां चढ़ते हैं,
चलती बसों पर सवार होने में माहिर,
पिछले सप्ताह, पहली बार, बस के फुटबोर्ड
पर पैर नहीं पड़ा। घायल तो नहीं हुए
लेकिन उनके अहंभाव पर बड़ी चोट लगी।
इस सप्ताह उन्होंने अपने जीवन में
महत्वपूर्ण फैसला किया।
वे नेशनल इंश्योरेंस में गये।
अनिल भार्गव अच्छी तरह समझ गये कि
उनके और उनके परिवार को
नेशनल इंश्योरेंस हाउस होल्डर्स पॉलिसी*
की बीमा-सुरक्षा की आवश्यकता है।

---

* हमारी नई हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिये आग और दंगा-फसाद, हड़ताल या दुर्भावनापूर्ण कार्य, आंधी, तूफान, बाढ़ और जलप्लावन, सेंधमारी, गृहवेध, चौर्य या चोरी जैसे संकटों के कारण घरेलू सामानों की होने वाली क्षति या हानि से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा, बीमा करानेवाला व्यक्ति, कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपनी पसन्द के अन्य दम देयता और साथ ही सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग, चौर्य या चोरी। जोखिमों से भी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ये बीमा सुरक्षा हैं: ऑल रिस्क्स, प्लेट-ग्लास, घरेलू उपकरणों की खराबी, टी.वी. सेट, पेड्ल साइकिल, अस्पताल में भर्ती तथा सरकारी

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे किसी भी कार्यालय से सम्पर्क कीजिए।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन एक प्रतिष्ठान)
सेवा है हमारा प्राथमिक कर्तव्य

CLARION C-NIC-21

विदेशी बैंकों में धन कैसे पहुंचता है ?

जिन लोगों को अपना धन विदेश ले जाने की जरूरत रहती है, वे इसके लिए अकसर चार तरीके अपनाते हैं।
१. आयात बीजकों में राशि बढ़ाकर,
२. निर्यात बीजकों में राशि घटाकर,
३. अघोषित दलाली या कम दलाली की घोषणा करके और, ४. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जरिये।

यदि आप आयातकर्ता हैं, तो आप आयात होनेवाली हर वस्तु का निर्धारित कीमत से अधिक का बीजक बनवायेंगे। मसलन, आपको १२०० करोड़ रुपए के हथियारों का आयात करना है, जिसमें आपकी घोषित दलाली सात प्रतिशत है, तो आप १४०० करोड़ रुपए का बीजक बनवायेंगे और उसका भुगतान करवायेंगे। तब हथियार बेचनेवाली फर्म द्वारा २०० करोड़ रुपए की बढ़ी राशि विदेश में जिस मुद्रा और खाते में आप चाहेंगे—जमा करा दी जायेगी और आपको खुले रूप में सात प्रतिशत दलाली (९८ करोड़ रुपए) का भुगतान भी कर दिया जायेगा। यदि इस सौदे में आप अपनी दलाली मात्र २ प्रतिशत घोषित करना चाहते हैं, तो हथियार बेचनेवाली फर्म आपको २ प्रतिशत दलाली (२८ करोड़ रुपए) का भुगतान खुले रूप में करेगी और शेष पांच प्रतिशत दलाली (७० करोड़ रुपए) की राशि चुपचाप आप जिस विदेशी खाते में जमा कराना चाहेंगे, जमा हो जायेगी। यदि आप अपने देश में अपनी साख बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि 'दलाली' की बात का किसी को पता न चले, तो आपकी समूची सात प्रतिशत दलाली (९८ करोड़ रुपए) आपके विदेंशी खाते में चुपचाप जमा करा दी जायेगी।

अब आप और अधिक धन विदेश ले जाना चाहते हैं, तो विदेशी सप्लायर के साथ प्रति व्यापार समझौता करेंगे। तब आप कहेंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा कोष सीमित है इसलिए आप आयात की गयी वस्तु की आधी कीमत विदेशी मुद्रा में और शेष आधी कीमत का भुगतान वस्तु के रूप में करेंगे। ऊपर से देखने पर लगता है कि इस सौदे में दलाली का नामोनिशान नहीं है, लेकिन वास्तव में आपने क्या किया ? मान लो आपको आधी कीमत के भुगतान के रूप में ८०० करोड़ रुपए का सामान उक्त फर्म को भेजना है, लेकिन आप सामान १२०० करोड़ का भेजते हैं, और बीजक ८०० करोड़ का बनाते हैं, जिससे यह लगे कि आपने ८०० करोड़ रुपए का ही सामान भेजा है। अब वह फर्म ८०० करोड़ रुपए का सामान तो आपके भुगतान खाते में एडजस्ट कर लेगी और अतिरिक्त सामान के ४०० करोड़ रुपए जिस बैंक में आप चाहेंगे आपके व्यक्तिगत धन के रूप में जमा करा देगी। आपको अपने द्वारा अतिरिक्त सामान के रूप में भेजे गये ४०० करोड़ रुपए के सामान को बेचने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसे बेचने की व्यवस्था उक्त फर्म ही करेगी। इस तरह निर्यात बीजकों में राशि घटाकर विदेश में काला धन पहुंचाया जाता है।

चौथा तरीका थोड़ा जोखिम भरा है। इसमें आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की कीमतों में आये उतार-चढ़ाव का फायदा उठाते हैं। मान लीजिए आपने किसी देश से २०० करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का सौदा किया है—मसलन स्वीडन से। इस बीच स्वीडिश मुद्रा क्रोनर की कीमत रुपए के मुकाबले बढ़ जाती है और स्वीडिश फर्म क्रोनर में ही भुगतान चाहती है, तो आपको दो सौ करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको पैसा खाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यदि क्रोनर की कीमत रुपए के मुकाबले घट जाती है, तो भी आप २०० करोड़ रुपए का ही भुगतान करेंगे। क्रोनर की कीमत घटने से जो अंतर आयेगा, वह धनराशि आपके विदेशी खाते में जमा हो जायेगी।

बोफोर्स के मामले में क्या हुआ ? इस मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति को बताया गया कि १० अक्तूबर, १९८५ को फ्रैंच और बोफोर्स द्वारा तोपों की बिक्री के लिए क्रमशः १३९४.७४ करोड़ व १४००.७२ करोड़ रुपयों का प्रस्ताव था। इसमें फ्रैंच तोपों की कीमत बोफोर्स तोपों से कम थी, लेकिन आगामी कुछ सप्ताहों में फ्रेंक (फ्रैंच मुद्रा) के मुकाबले रुपए की कीमत घट गयी, जबकि क्रोनर (स्वीडिश मुद्रा) के मुकाबले रुपए की कीमत उतनी नहीं घटी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय रुपए में फ्रैंच तोपों का सौदा बोफोर्स तोपों से महगा हो गया। २१ मार्च, १९८६ को फ्रैंच तोपों की कीमत १४३६.७६ करोड़ थी और बोफोर्स तोपों की १४२७.०२ करोड़। इस प्रकार बोफोर्स तोपों का सौदा फ्रैंच तोपों के मुकाबले ९.७४ करोड़ रुपए सस्ता हो गया और इसके कुछ ही घंटों बाद बोफोर्स के अधिकारी दिल्ली उड़ चले और ४८ घंटों में बोफोर्स तोपों के सौदे पर हस्ताक्षर हो गये।

लेना होता। यह कंपनी और कोई नहीं, केवल थापर की होती या फिर उनके द्वारा सुझायी गयी। यह सामान स्वीडन की कंपनी के पास जाता और बढ़ा हुआ धन स्विस बैंकों में जमा होता। यह अपने आप में नायाब तरकीब थी। यदि मामला खुलता, तो 'फेरा' उल्लंघन के आरोप में थापर या किसी वी०वी०आई०पी० की शामत नहीं आती, बल्कि त्रेहान की आती। इस खतरे को उठाने के लिए त्रेहान तैयार हो गये, क्योंकि उसकी उन्हें २ प्रतिशत कमीशन के रूप में कीमत मिलनी थी। यह कीमत १६ करोड़ रुपए होती, क्योंकि सौदा ८०० करोड़ रुपए का था। लेकिन रंग में भंग पड़ गया।

रहस्योद्‌घाटन: गत अप्रैल में संसद में के०पी० उन्नीकृष्णन ने सवाल पूछा था कि क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बोफोर्स के साथ बदले के व्यापार का कोई करार हुआ है? इस सवाल का उत्तर बजट सत्र में नहीं मिला। अभी जब शरदकालीन सत्र शुरू हुआ, तो प्रियरंजन दास मुंशी ने स्वीकार किया कि राज्य व्यापार निगम के जरिये आपसी व्यापार का समझौता हुआ है। बताया जाता है कि ऐसी कोशिशें हुईं कि यह सवाल न उठे और कोई उत्तर न दिया जाये, लेकिन अध्यक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया।

यह गौर करनेवाली बात है कि समझौते के समय एस०टी०सी० के अध्यक्ष सुधीर मूलजी थे जो प्रधानमंत्री की 'पसंद' माने जाते थे। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अगस्त में वह एस०टी०सी० छोड़ गये और लंदन चले गये। मूलजी, एस० टी०सी० से हटने का कारण 'खराब सेहत' बताते हैं, मगर सूत्रों का कहना है कि बोफोर्स कांड के कारण वह हटे। बताया जाता है कि रहस्य तब और गहरा हो गया, जब मूलजी के जाने के बाद एक मंत्री ने एस०टी०सी० से संबंधित सभी फाइलें मांगी। यद्यपि अधिकारियों ने यह कह कर फाइलें देने से इनकार कर दिया कि उन्हें लिखित आदेश चाहिए। कहा जाता है, बाद में एक वी०आई०पी०, एस०टी०सी० आफिस से उक्त सौदे से संबंधित सारी फाइलें ले गया। उसके बाद से इस सौदे के बारे में कुछ नहीं सुना गया। राज्य व्यापार निगम कृषि उत्पादनों, धातुओं और खनिजों का निर्यात करता है, जिसका बोफोर्स से शायद ही कोई लेना-देना हो। तब बोफोर्स कंपनी इस सौदे के लिए क्यों तैयार हो गयी ? और सरकार ने बोफोर्स की मार्फत यह निर्यात करने की क्यों ठानी ? क्या बोफोर्स के साथ हुए इस समझौते से यह नहीं जाहिर होता कि इस दलाली कांड की जड़ें काफी गहरी हैं और इन्हें बड़े-बड़े लोगों ने सींचा है ?

–दिल्ली ब्यूरो

सूखे के बावजूद अन्न का निर्यात

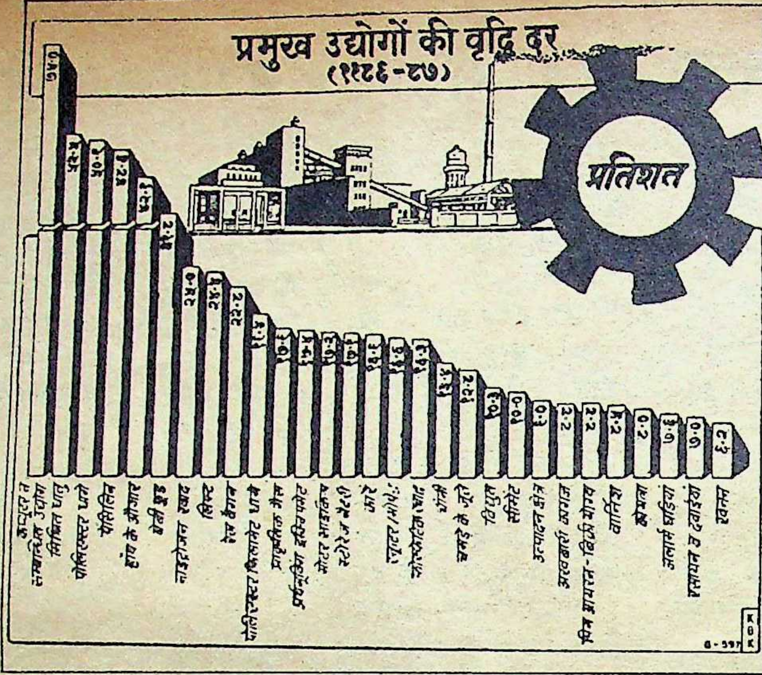

देश सूखे और बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन भारत सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच २.२७ लाख मीट्रिक टन गेहूं और १.८० लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया और कोरिया तथा नेपाल को पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने का करार किया है।

देश में बाढ़ से इस वर्ष १५६५ व्यक्तियों की मौत हुई तथा ७६९२० पशु मारे गये तथा ५ करोड़, १५ लाख ९२ हजार लोग प्रभावित हुए, दूसरी ओर सूखे का २८ करोड़, ५४ लाख, ४५ हजार आबादी तथा १६ करोड़, ३६ लाख, ८४ हजार पशुओं पर प्रभाव पड़ा।

पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति के धीमी होने के कारण समय-आकलन में गड़बड़ी न हो, इसलिए वर्ष १९८७ के समाप्त होने पर एक सैकेण्ड के लिए पूरी दुनिया की मानक घड़ियां बंद कर दी जायेंगी। इस प्रकार वर्ष १९८८ का प्रारंभ एक सैकेण्ड विलंब से होगा।

इस समय ३३७ उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, इनमें सोवियत रूस के १४६, अमरीका के १२९ तथा शेष ६२ अन्य १३ राष्ट्रों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हैं। सोवियत रूस के दो तिहाई तथा अमरीका के आधे से अधिक उपग्रह सैन्य कार्यों के लिए हैं।

भारत के औद्योगिक घरानों में संपत्ति के मामले में बिड़ला घराने ने बाजी मार ली है। उसकी संपत्ति ४१ अरब, ११ करोड़, ५५ लाख रुपए है और उसने १९८५ के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १५४ करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। पहले टाटा घराना कुल संपत्ति के मामले में अव्वल था—अब दूसरे नंबर पर उतर आया है। उसकी कुल संपत्ति ३६ अरब ९८ करोड़ ८४ लाख रुपए है, लेकिन मुनाफा कमाने के मामले में वह बिड़ला घराने से बहुत आगे है। उसने २५१ करोड़ ८३ लाख रुपए का मुनाफा कमाया। चोटी के २० औद्योगिक घरानों में तीसरा नाम था पर (१०६७.८६ करोड़ रुपए) का है। इस दौड़ में आई०टी०सी० (इंडियन टोबेको कंपनी) कंपनी पिछड़ गयी है और एक नये घराने एम०ए० चिदंबरम ने चोटी के बीस घरानों में सातवां स्थान प्राप्त कर लिया है।

बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इन चार महानगरों में १७ प्रतिशत मध्यवर्गीय विवाहित महिलाएं नौकरी करती हैं, साथ ही घर का काम-काज भी। इस प्रकार एक कामकाजी महिला को लगभग १८ घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है।

उद्योग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के २७ उपक्रमों को एक-एक करोड़ या उससे अधिक का घाटा हुआ।

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार १९८५-८६ के दौरान औद्योगिक विकास की दर ८.७ प्रतिशत थी जो १९८६-८७ में बढ़कर ८.९ प्रतिशत हो गयी है।

इस वर्ष लघु बचत के अंतर्गत ४२०० करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है।

गत वर्ष तस्करों से २१७४ किलो सोना, ८७८९ किलो अफीम, ६०६१९ किलो गांजा, २६२१ किलो हेरोइन, २०७ किलो मारफीन तथा १४८४ किलो मेंड्रेक्स की गोलियां पकड़ी गयीं।

एयर इंडिया का एक विमान हेरोइन ले जाता हुआ नाइजीरिया के लागोस हवाई अड्डे पर पकड़ा गया, जहां ५८ दिनों तक वह रोककर रखा गया, जिससे एयर इंडिया को ४ करोड़ ५९ लाख रुपए की क्षति हुई।

आतंकवादी हिंसा त्रिपुरा में भी जारी है। वहां इस वर्ष टी०एन०वी० आतंकवादी संगठन ने अभी तक ६० हत्याएं कर दी हैं।

देश में अभी तक १५ एड्स रोगियों की पुष्टि हुई है। गत अक्तूबर तक भारत में ५६९६० लोगों की जांच की गयी, जिनमें १४५ लोगों में एड्स के प्रारंभिक लक्षण पाये गये हैं।

इस वर्ष मई से सितंबर के दौरान १०४२ पाक. घुसपैठिए जासूस पकड़े गये जिनमें से ९४८ जासूसों को वापस खदेड़ दिया गया जबकि ९४ पुलिस की हिरासत में हैं। इसी प्रकार अप्रैल, १९८६ से, मार्च, १९८७ की अवधि में राजस्थान सीमा पर १७ पाक जासूस पकड़े गये।

केंद्र सरकार द्वारा १९७८-७९ से यह योजना लागू है कि मद्यनिषेध को प्रोत्साहन देने में जिस प्रदेश को शराब की बिक्री में जितना घाटा होगा, केंद्र उस प्रदेश को उस घाटे का पचास प्रतिशत मुआवजे के रूप में देगा, लेकिन आश्चर्य है कि पिछले दस वर्षों में किसी भी प्रदेश ने इस मुआवजे की मांग नहीं की है।

ताजा अनुमानों के अनुसार देश में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या ४० लाख है। पिछले तीन वर्षों में साढ़े १२ लाख से अधिक कुष्ठ रोगियों का पता चला और इस अवधि में करीब साढ़े ११ लाख कुष्ठ रोगी इलाज के बाद ठीक हो गये।

पूरी दुनिया में ५० लाख महिलाएं, हर वर्ष प्रसव के समय मर जाती हैं। ऐसी ९९ प्रतिशत मौतें विकासशील देशों में होती हैं। हर वर्ष पूरी दुनिया में ५ से ६ करोड़ महिलाएं गर्भपात कराती हैं और गर्भपात की गड़बड़ियों से हर वर्ष २ लाख महिलाओं की मौत हो जाती है। विकसित देशों में एक महिला औसतन दो बच्चों को जन्म देती है, जबकि अविकसित देशों में यह औसत छह या सात है। शरीर वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी १८ वर्ष से कम आयु की महिलाओं की संख्या बहुत कम होती हैं जो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें, फिर भी अफ्रीका और एशिया के देशों में औसतन १६ वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह हो जाता है और १७ वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते वे संतान पैदा करना शुरू कर देती हैं।

पूरी दुनिया में प्रति वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से एक करोड़ ६७ लाख बच्चों का पैदा होते समय वजन अपेक्षित मात्रा से कम होता है। एक करोड़ बच्चे पैदा होने के १२ महीनों में और ४० लाख बच्चे एक से पांच साल की उम्र में मर जाते हैं। ऐसी ९८ प्रतिशत मौतें अविकसित देशों में होती हैं। इनमें ५० लाख मौतें कुपोषण से, ४० लाख मौतें खसरा से, ३० लाख मौतें मलेरिया से और ८ लाख मौतें टिटनेस से होती हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के ६८ उद्योग गंगा में कूड़ा-कचरा फेंकते हैं।

संकलन : विनोद मिश्र

"क्या कहा, वक़्त का मोल?
आशा और निराशा के बीच है
तो बस... एक पल!"

आपकी ज़िन्दगी का यह वक़्त...
हर लम्हा हर पल इक खज़ाना है बेशकीमती.
वक़्त की कद्र आपकी नज़रों में
है कितनी यह साफ़ झलकता है
आपकी बोल-चाल, चाल-ढाल
हर काम में... हर कामयाबी में...
ज़िन्दगी के हर छोटे-बड़े इम्तिहान में!
और झलकता है इन सबसे ज्यादा
कलाई पर आपकी -
आपकी कलाई-घड़ी की पहचान में.

TIMESTAR
क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ
सौ से भी ज़्यादा डिज़ाइनों में.

मोल अनमोल... वक़्त का
और आपके पैसों का.

Avenues.TS.55.87

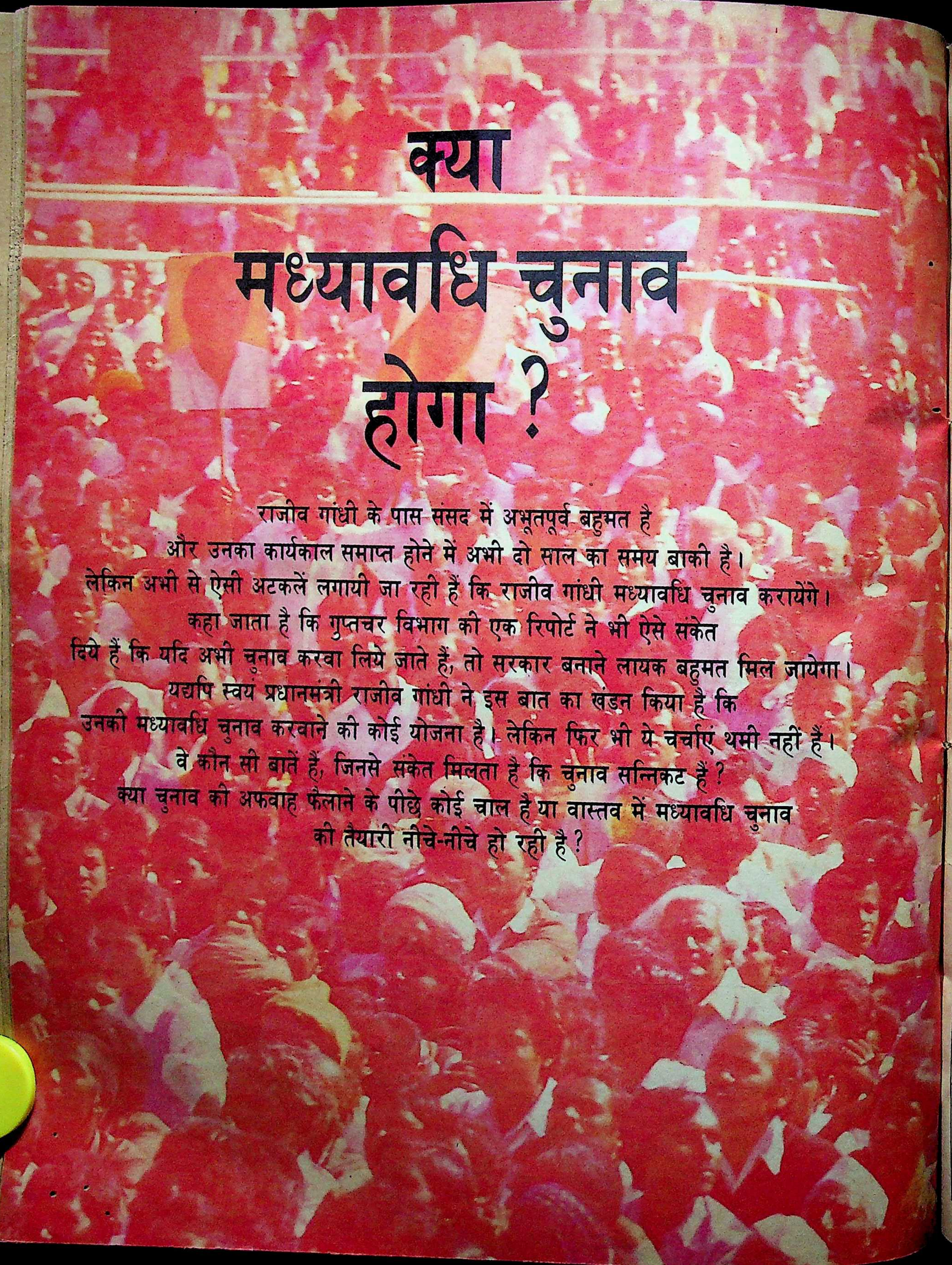

क्या मध्यावधि चुनाव होगा ?

राजीव गांधी के पास संसद में अभूतपूर्व बहुमत है
और उनका कार्यकाल समाप्त होने में अभी दो साल का समय बाकी है।
लेकिन अभी से ऐसी अटकलें लगायी जा रही हैं कि राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव करायेंगे।
कहा जाता है कि गुप्तचर विभाग की एक रिपोर्ट ने भी ऐसे संकेत
दिये हैं कि यदि अभी चुनाव करवा लिये जाते हैं, तो सरकार बनाने लायक बहुमत मिल जायेगा।
यद्यपि स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात का खंडन किया है कि
उनकी मध्यावधि चुनाव करवाने की कोई योजना है। लेकिन फिर भी ये चर्चाएं थमी नहीं हैं।
वे कौन सी बातें हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि चुनाव सन्निकट हैं ?
क्या चुनाव की अफवाह फैलाने के पीछे कोई चाल है या वास्तव में मध्यावधि चुनाव
की तैयारी नीचे-नीचे हो रही है ?

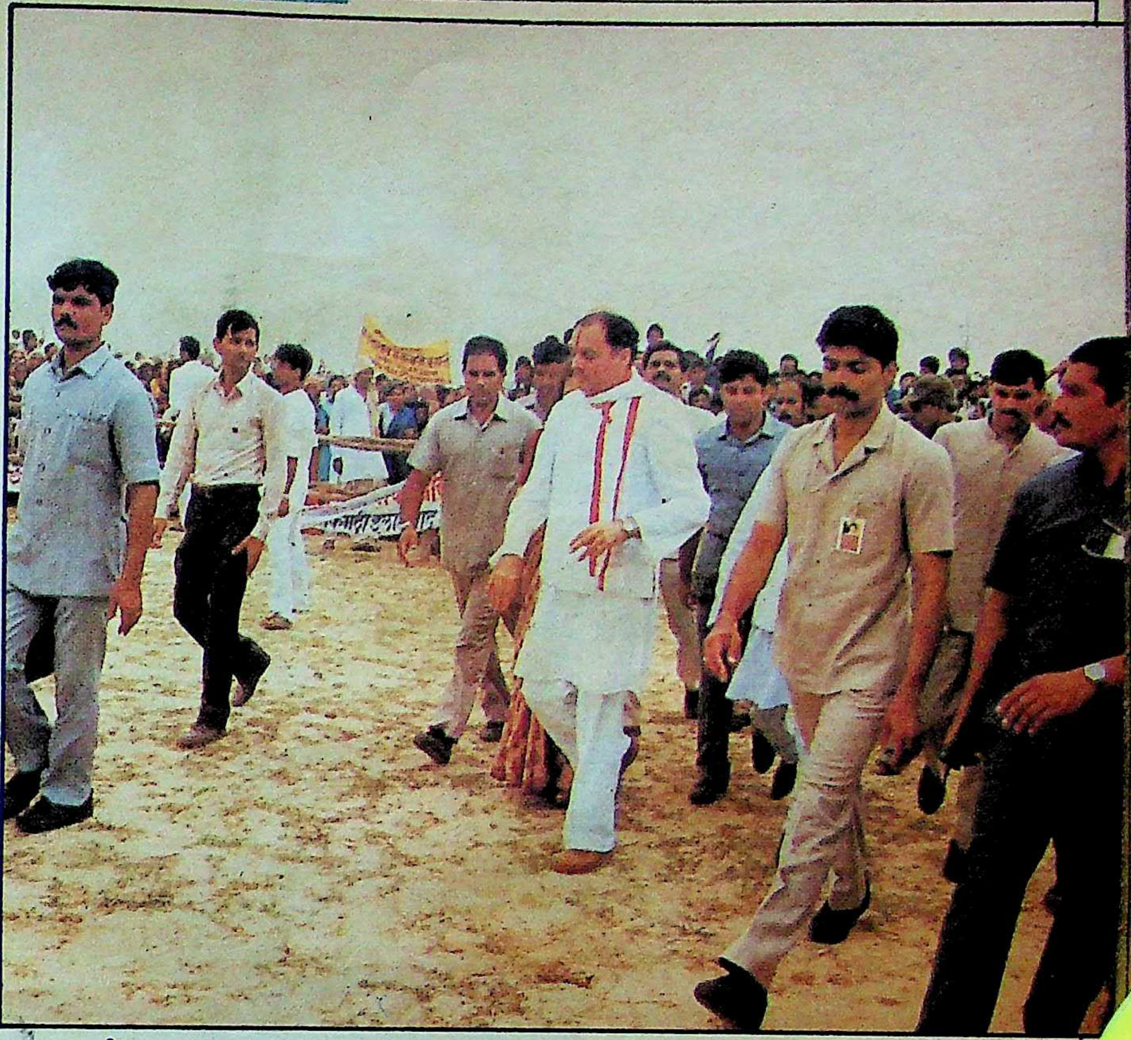

जनाधार की थाह

छाया: मनमोहन शर्मा

१९८४ की अभूतपूर्व सफलता का सेहरा बांधने के बाद राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी अथवा क्षत-विक्षत विपक्ष ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार की नैया मझधार में डगमगाने लगेगी और मांझी को किनारे की खोज में हर संभव उपाय के लिये हाथ-पैर मारने पड़ेंगे। इसी माहौल का नतीजा है कि मध्यावधि चुनाव तक की चर्चाएं गर्म हो रही हैं।

प्रारंभ में विपक्ष की संकटों, विवादों और संदेहों के चक्रव्यूह में फंसे राजीव गांधी से मध्यावधि चुनाव कराने की मांग को सरकार ही ने नहीं, आम जनता ने भी कान नहीं दिया था। किंतु हाल की कुछ रिपोर्टों और देश के सामने पेश ज्वलंत समस्याओं ने मध्यावधि चुनाव की संभावना के मुद्दे को उठाकर सरकार सहित सभी विपक्षी खेमों में उथल-पुथल मचा दी है। विशेषकर इसलिए किं यह समाचार सर्वप्रथम सरकार के नजदीक माने जाने वाले दैनिक 'टाइम्स आफ इंडिया' के मुखपृष्ठ पर छपा था। इस संबंध में दैनिक ने दलील दी थी कि मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल स्थगित करना इस बात का संकेत है कि राजीव गांधी जल्द ही मध्यावधि चुनाव कराने की योजना बना रहे हैं।

खंडन: सूचना सच रही हो या मनगढ़ंत, प्रधानमंत्री के लिए इसका खंडन करना न अप्रत्याशित था न आश्चर्यजनक। मध्यावधि चुनाव की रहस्यात्मकता बनाये रखना किसी भी सरकार के लिए हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें उन्हें गुपचुप तैयारी करने और विपक्ष को गाफिल रखने का भरपूर मौका मिलता है। यह बात राजीव गांधी सहित अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता भलीभांति जानते हैं। अतः उनके इनकार से यदि चर्चा और विवाद शान्त नहीं हुआ है, तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है।

वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए यह 'अफवाह' चिता का विषय बन गयी है। आम कांग्रेसी बार-बार यही सवाल करता है कि आजादी के इतिहास में उनकी पहली सबसे प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार को मध्यावधि चुनाव कराने की क्या पड़ी है? लहू-लुहान विपक्ष को मरहम-पट्टी करने का सुनहरा मौका देने की जरूरत क्या है? पार्टी महासचिव केदार नाथ सिंह मध्यावधि चुनाव की चर्चा को 'अस्थिरता फैलाने का एक नया हथकंडा' करार देते हुए कहते हैं, "केवल मूर्ख ही मध्यावधि चुनाव की बात फैला रहे हैं। दरअसल यह काम राजनीतिक षड्यंत्रकारियों का एक समझा-बूझा खेल है। राजीव गांधी और पार्टी के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों में मुंह की खाने के बाद अब वे ऐसी बेसिरपैर की उड़ानों से देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं।"

विपक्ष की राय सर्वथा भिन्न है। लगभग सभी गैरकांग्रेसी दलों का मत यही है कि यह समाचार कांग्रेस द्वारा स्वयं 'लीक' किया गया है। अपने दावे की पुष्टि में वह अनेक तर्क पेश करते हैं। मसलन जनता, विपक्षी दलों और स्वयं कांग्रेसियों को तौलने

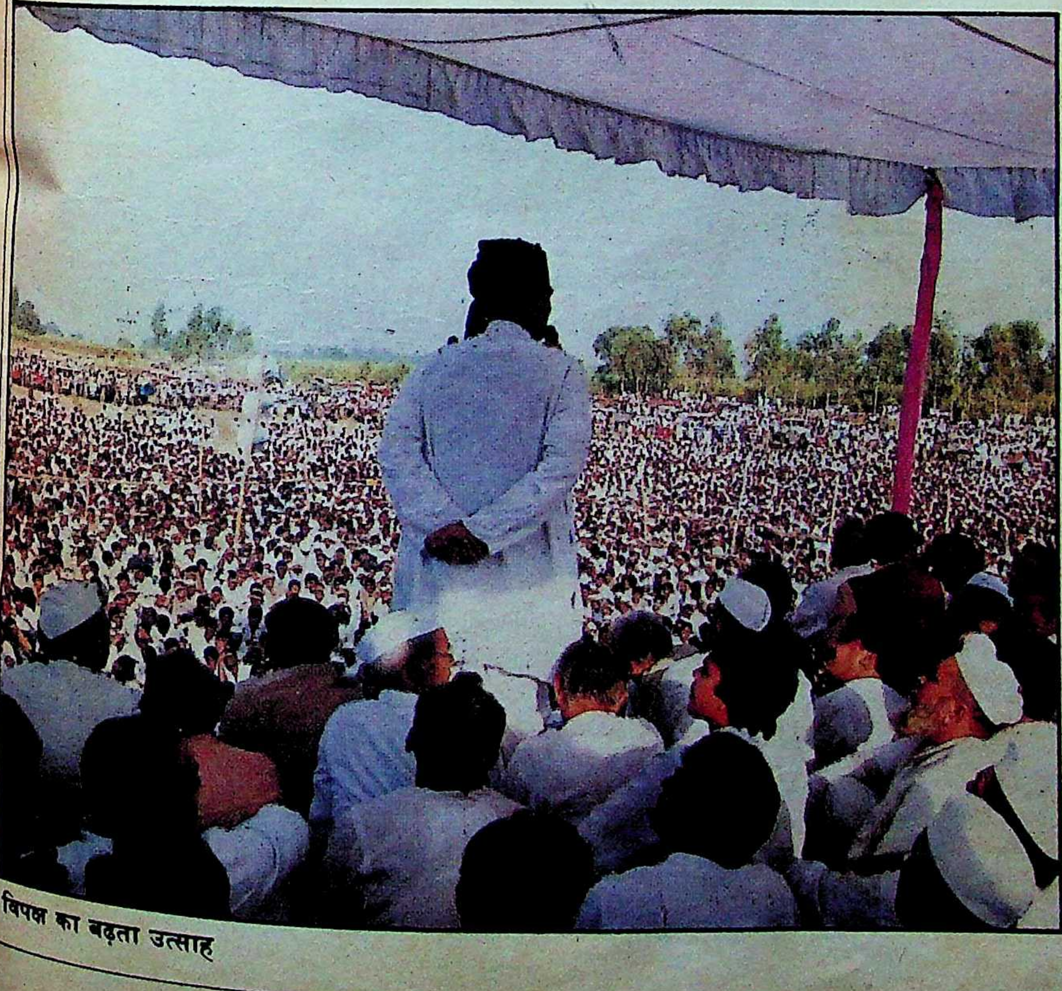

विपक्ष का बढ़ता उत्साह

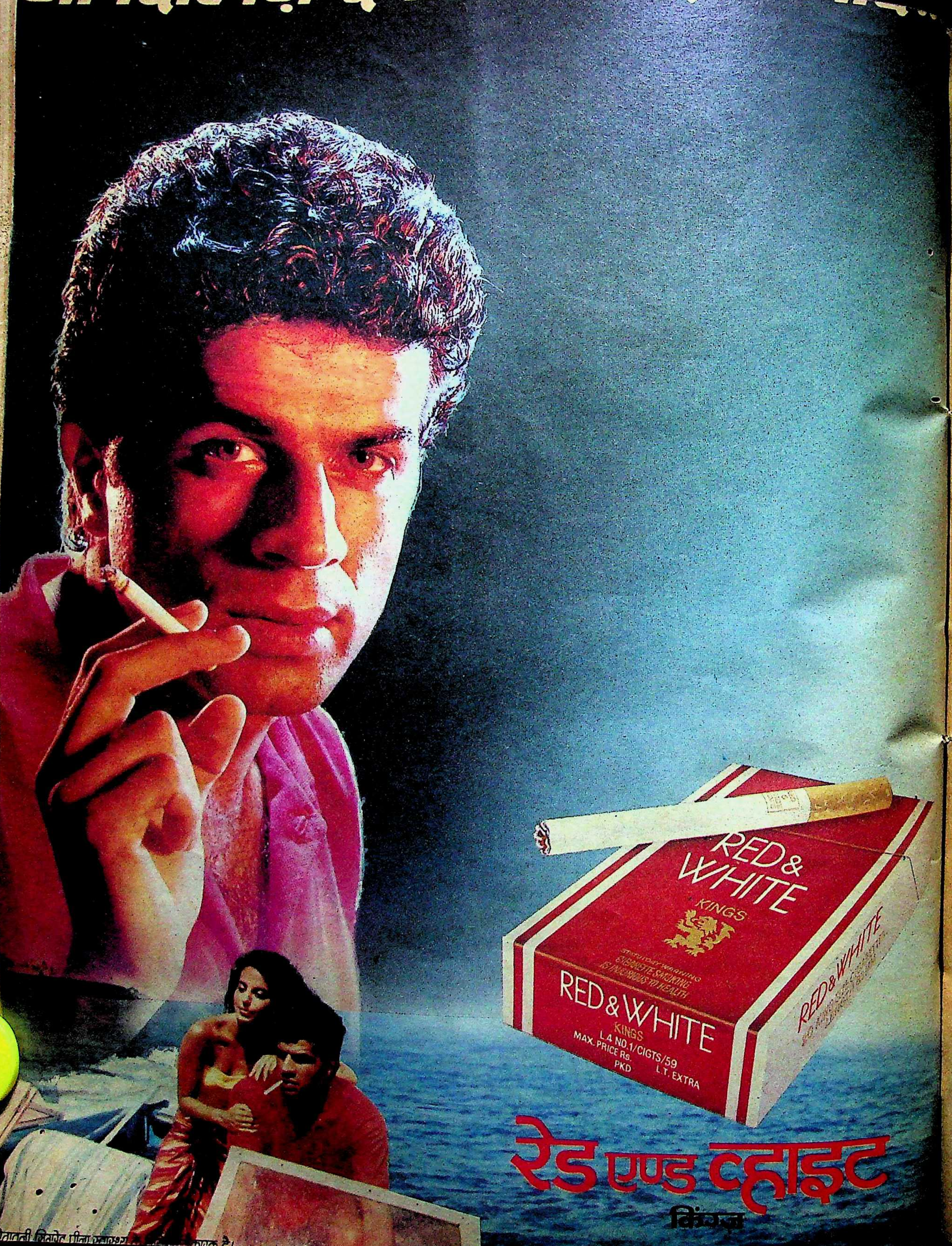

RED & WHITE
KINGS
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH
RED & WHITE
KINGS
L.4 NO.1/CIGTS/59
MAX. PRICE Rs.
PKD
L.T. EXTRA
RED & WHITE
रेड एण्ड व्हाइट
किंग्ज़
चेतावनी: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

व उनके विचारों को जानने के लिए यह बात फैलायी गयी है। रिपोर्ट का समय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संसद के शीतकालीन अधिवेशन के प्रारंभ के ऐन पहले ऐसा समाचार छापने का लक्ष्य उन सभी असंतुष्ट कांग्रेसियों को चेतावनी देना था जो अनिर्णय की स्थिति में कोई भी पार्टीविरोधी कदम उठाने की ताक में हैं। वरिष्ठ मार्क्सवादी सासंद सोमनाथ चटर्जी ने 'माया' से कहा, ''यह खबर कांग्रेसी सांसदों के सिर पर लटकती तलवार है, जिससे उन पर काबू रखा जा सके।''

कांग्रेस में वर्षों रह चुके एक बुजुर्ग नेता ने बताया कि असंतुष्ट और विद्रोही कांग्रेसियों पर लगाम लगानें के लिए ऐसे ही अनेक तरीकों का श्रीमती गांधी भी समय-समय पर सफलतापूर्वक उपयोग करती रही हैं। ''राजीव गांधी ने भले ही अपनी मां की अन्य बातों का अनुसरण न किया हो, किंतु हाल के अस्थिर, अस्पष्ट राजनीतिक परिदृश्य ने उन्हें कांग्रेसियों को नियंत्रण में रखने के सभी हथकण्डे अच्छी तरह सिखा दिये हैं।''

मतदाता को विकल्प चाहिए

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

जहां तक कांग्रेसियों को वश में करने की बात है, वह कांग्रेस-स के के०पी० उन्नीकृष्णन के अनुसार, ''कोई कठिन काम नहीं है, केवल पेंशन के प्रलोभन और भत्ते में वृद्धि से सारे-के-सारे कांग्रेसी सांसद खरीदे जा सकते हैं। यही तरीका राजीव गांधी संसद के इस सत्र में एक विधेयक द्वारा अपनाने वाले हैं।''

कुछ समय पहले फैली मंत्रिमंडल में प्रत्याशित फेरबदल की खबर भी पार्टी और सांसदों को एकजुट करने में काफी सफल सिद्ध हुई है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर कहते हैं: लगभग १५० सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सब्जबाग दिखाया गया और अन्य आधा दर्जन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पद का प्रलोभन दिया गया। नतीजतन राजीव गांधी मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल करने में बराबर आनाकानी करते रहे हैं, क्योंकि फेरबदल में केवल मुट्ठी भर लोगों की ही मुराद पूरी की जा सकती है। इससे असंतुष्टों की संख्या में होने वाली भारी वृद्धि के कारण पार्टी और सरकार दोनों को हानि पहुंच सकती है।

संकेत : नायर की रिपोर्ट छपने के दो दिन पूर्व दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा का मुख्य विषय यह था कि रिपोर्ट की पूरी जानकारी हासिल करने व उसको छपने से रोकने के लिए गुप्तचर विभाग भारी दौड़-धूप कर रहा है। कारण इससे राजीव गांधी की कार्यशैली का जो पर्दाफाश होगा, उससे पार्टी सदस्यों और जनता में उनकी विश्वसनीयता को भारी धक्का लगेगा। किंतु भरपूर कोशिशों के बावजूद रिपोर्ट छपी, जिसकी तमाम दलीलें अपने में सही हो सकती हैं। किंतु इसमें एक अन्तर्विरोध यह है कि मंत्रिमंडलीय फेरबदल न करने को मध्यावधि चुनाव की संभावना का एक स्पष्ट संकेत भी माना जा रहा है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकेत भी मध्यावधि चुनाव की संभावना को प्रबल बनाते हैं। जनता पार्टी महासचिव यशवंत सिन्हा ने इस विषय पर 'माया' से चर्चा करते हुए कहा, ''राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देते समय प्रायः हम कुछ महत्वपूर्ण मसलों को अनदेखा कर जाते हैं जैसा कि इस वाद-विवाद के दौरान हो रहा है। हम मध्यावधि चुनाव को केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं, जबकि आर्थिक मुद्दा कहीं अधिक प्रभावी और निर्णायक सिद्ध हो सकता है।''

सिन्हा सहित अनेक राजनीतिज्ञ एक मत हैं कि देश की आर्थिक स्थिति विषम है जो आने वाले समय में लगातार विकराल रूप धारण करती जायेगी। मुद्रास्फीति में बराबर बढ़ोत्तरी होने की पूर्ण संभावना है। इस वर्ष का अभूतपूर्व सूखा व श्रीलंका में हो रहा प्रतिदिन ३ करोड़ रुपए से अधिक का व्यय दोनों देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर देंगे। राजीव सरकार के पास अगले वर्ष काफी कड़ा बजट पेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा न होगा। बढ़ती महंगाई की जबर्दस्त मार से त्रस्त जनता ही नहीं, कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ने में नहीं हिचकिचायेंगे।

लोकदल-ब के अध्यक्ष अजीत सिंह के अनुसार, ''स्थिति में किसी प्रकार के सुधार की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखायी देती। स्वयं कांग्रेसी नेता जिनका सीधा जनसंपर्क है, मानते हैं कि राजीव गांधी की अटपटी कार्यशैली उन्हें श्रीलंका जैसी गलती पर गलती करने को बाध्य करती रहेगी। भ्रष्टाचार और अराजकता के बोलबाले में बढ़ोत्तरी होगी और प्रशासन में दिन-दूनी रात चौगुनी गिरावट आयेगी। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी-से-जल्दी चुनाव करा लिये जायेंगे, उतना ही पार्टी और सरकार के हित में रहेगा।''

उमाशंकर दीक्षित जैसे वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता को पार्टी के सांगठनिक चुनाव और सदस्यता की जांच-पड़ताल का जो कार्यभार सौंपा गया था, उसके सिलसिले में पेश अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता शीघ्रातिशीघ्र सांगठनिक चुनाव कराने के पक्ष में हैं। यह पार्टी के आम कार्यकर्ता के बढ़ते हुए असंतोष, संशय और बेचैनी का तो द्योतक है ही, साथ ही यह भी आभास मिलता है कि पार्टी को किसी अहम और निर्णायक काम के लिए चुस्त-दुरुस्त किया जा रहा है।

पार्टी और स्वयं राजीव गांधी द्वारा हाल की अपनायी गयी आक्रामक मुद्रा का भी एक विशेष अर्थ है। ऐसी आम धारणा है। देश के गैरकांग्रेसी शासित राज्यों के अलावा उ०प्र०, महाराष्ट्र, गुजरात, म०प्र० और पंजाब आदि राज्यों में जिस ढंग से कांग्रेसी अभियान चलाया जा रहा है, वह जहां वी०पी० सिंह के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेसियों को एकजुट करने का प्रयास माना जा रहा है, वहां इस लुंज-पुंज पार्टी में प्राण फूंकने और चुनावी तैयारी का भी पूर्वाभ्यास माना जा रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि प० बंगाल में रडन स्क्वेयर नामक पार्क के मसले को लेकर कांग्रेस ने जो तूफानी अभियान चलाया, उसकी अगुवाई कोई और नहीं, बल्कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्यमंत्री दासमुंशी कर रहे थे। पार्टी के आक्रामक रुख का इससे अच्छा उदाहरण कोई अन्य नहीं।

यही नहीं, विभिन्न राज्यों में चलाये गये सूखा राहत कार्यों में सरकारी मशीनरी से कहीं अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की शिरकत और साझेदारी पर अधिक बल देने को भी चुनाव के मैदान में उतरने के पहले की आवश्यक कवायद समझा जाता है। भारतीय राजनीति में प्याज एक निर्णायक मुद्दा है। जनता शासन के पतन और इंदिरा गांधी की वापसी

क्या मध्यावधि चुनाव का परिणाम होगा खिचड़ी सरकार?

मध्यावधि चुनाव की संभावना पर कांग्रेस को १९८४ जैसा प्रचंड बहुमत मिल पायेगा यह आशा शायद प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक नहीं कर रहे होंगे। चुनाव विशेषज्ञों और जनमत संग्रहों के अनुसार कांग्रेस अधिक से अधिक ३०० सीट प्राप्त कर पायेगी। अतः या तो वह बहुत थोड़े से बहुमत के साथ सरकार बना पायेगी या विपक्षी पार्टियों की खिचड़ी सरकार बनेगी। इस संबंध में 'माया' द्वारा विपक्षी नेताओं से की गयी बातचीत के अंश:

भारतीय राजनीति के अखाड़े के मंजे हुए खिलाड़ी, लोकदल (ब) के अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा ने केन्द्र में एक खिचड़ी सरकार बनने की संभावना व्यक्त की है, जिसे वे राष्ट्रीय सरकार कहना पसंद करते हैं। 'माया' से बातचीत में उन्होंने कहा "मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जनता का रुझान कांग्रेस-इ का विकल्प ढूंढ़ने और मिली-जुली सरकार बनाने की ओर है। जनता सरकार आपात स्थिति की उपज थी इसलिए उसके राजनीतिक अस्तित्व का विकास नहीं हुआ, पर अब जो सरकार बनेगी उसकी जड़ें जन संघर्ष में होंगी।"

दरअसल, साठ के दशक से ही कांग्रेस के प्रति जनाक्रोश उभरना शुरू हुआ तथा कांग्रेस के विकल्प ढूंढ़ने के प्रयास भी हुए। समाजवादी नेता डा० राम मनोहर लोहिया ने सातवें दशक के उत्तरार्ध में गैर-कांग्रेसवाद का नारा देकर जनता के कांग्रेस के विकल्प के रूप में संविद अथवा मिलीजुली सरकार के सोच को अभिव्यक्ति दी। इसके बाद जहां भी जनता को कोई विकल्प दिखा उसने उसको चुना भी। यह अलग बात है कि कांग्रेस तथा वामपंथियों के प्रभुत्व वाली साझा सरकार को छोड़कर, १९६७ की उ०प्र०, बिहार, पंजाब, हरियाणा की संविद सरकारें टूट गयीं और फिर चुनाव कराने पड़े। यही हाल १९७७ की जनता सरकार का भी हुआ। उसने जनता को निराश तो जरूर किया है, पर हताश नहीं। जनता पार्टी की विफलता से नाराज जनता ने '८० में श्रीमती गांधी को भारी मतों से चुना तो सही, पर कुछ समय बाद राज्यों के चुनावों में जहां जो भी विकल्प उसे मिला उसने उसे चुना। १९८४ में श्रीमती गांधी की हत्या से उपजी करुणा ने राजीव गांधी को जो विशाल बहुमत दिलाया वह अब इतिहास की बात हो गयी है। शायद आज वह भारतीय इतिहास के सबसे अधिक विवादग्रस्त प्रधानमंत्री हैं। यदि दल-बदल विरोधी कानून नहीं होता, तो वे सत्ता में टिक पाते इसमें संदेह है। मध्यावधि चुनाव की स्थिति में वह वैतरिणी पार करते हैं या मिली-जुली सरकार बनती है, यह तो वक्त ही बतायेगा।

बहरहाल, जनता में आज जितना गुस्सा, असंतोष, बेचैनी राजीव सरकार के प्रति है, उतनी आजादी के बाद से शायद किसी सरकार के खिलाफ नहीं थी। और यह भी सच है कि विपक्ष आज पहले से कहीं ज्यादा बिखरा और लुंज-पुंज है। वी०पी० सिंह अवश्य ही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के कारण जनता के नेता बनने की स्थिति में हैं, किंतु उनके सहयोगी अरुण नेहरू तक मानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि जनता का गुस्सा राजीव सरकार के प्रति कम हो गया। राष्ट्रीय संजय मंच के नेता अकबर अहमद 'डम्पी' कहते हैं, "कोई भी अकेली पार्टी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। वी०पी० सिंह अधिक से अधिक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं।"

आज देश में १४ राज्यों में न केवल गैर कांग्रेसी सरकारें चल रही हैं बल्कि उन्हें वहां की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। लोकदल (ब) के महामंत्री शरद यादव मानते हैं कि कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से क्षुब्ध जनता को जहां जो भी दल या व्यक्ति विकल्प की सामर्थ्य रखता दिखता है वह उसी को सत्ता सौंप देती है। प० बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, केरल तथा हरियाणा इसके उदाहरण हैं। इसी सूत्र को वे केन्द्र में वैकल्पिक सरकार के स्वरूप का आधार मानते हैं।

भाजपा नेता जसवंत सिंह मानते हैं, "राजीव सरकार का इकबाल और उनकी इज्जत इस हद तक समाप्त हो गयी है कि उसका लौटना मुश्किल है। अगले दो वर्ष प्रतिपक्ष के लिए चुनौती भरे हैं। विपक्ष किस हद तक अपनी इस जिम्मेदारी को समझकर जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाह कर पायेगा? साझा सरकार अथवा अन्य विकल्प जो उसके पास होंगे उसके द्वारा वह जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है।"

प० बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु कहते हैं, "यदि केन्द्र में १९७७ की जनता सरकार जैसी कोई सरकार भाजपा को बाहर रखते हुए बनती है, तो हमारी पार्टी उसका समर्थन बाहर रहकर करेगी।" इसी बात को मार्क्सवादी के ही पोलित ब्यूरो के युवा सदस्य सीताराम येचुरी इस प्रकार कहते हैं "माकपा किसी भी सरकार में तब तक शामिल नहीं होगी जब तक कि उसकी स्थिति प्रभावी रूप से निर्णयों में हस्तक्षेप करने लायक न हो।"

भाजपा तथा माकपा दोनों ही पार्टियां यह तो मानती हैं कि केन्द्र में साझा सरकार की संभावनाएं हैं। पर दोनों एक-दूसरे को इससे अलग देखना चाहते हैं।

राष्ट्रीय संजय मंच की अध्यक्ष मेनका गांधी को पूरा यकीन है "इस देश के लोग विपक्षी दलों को एक मौका और सरकार चलाने के लिए देंगे। परंतु यदि विपक्षी दल इसको भी, १९७७ की तरह आपसी लड़ाई-झगड़ों में गंवा देते हैं, तो शायद तीसरा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। साझा सरकार से बेहतर होगा यदि हम सब लोग मिलकर एक पार्टी बनाकर जनता के सामने जायें तथा आगामी दो सालों में साथ रहकर काम करना सीखें।"

कांग्रेस (स) नेता के०पी० उन्नीकृष्णन मानते हैं बाएं बाजू की एक नयी पार्टी ही एक मजबूत विकल्प हो सकती है। यह विलयन होकर, १९७७ जैसी भावना से ओतप्रोत नयी पार्टी हो। तब यह बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को भी आकर्षित करेगी।

जनता पार्टी के नेता मधु दंडवते केन्द्र में साझा सरकार की संभावनाओं को काल्पनिक सवाल मानते हुए कहते हैं, "अभी दिल्ली दूर है।" यह विलय तथा खिचड़ी सरकार की बातें तो कुरसी के दावेदारों की हैं, जो जन-संघर्षों से बचना चाहते हैं। असली विकल्प तो जनसंघर्षों से ही निकलनेवाला है। उसके लिए साझा मंच तैयार कर एक आंदोलन चलाना चाहिए।"

समाजवादी चिंतक मधु लिमये देश की भावी राजनीति को इस बात पर निर्भर मानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा शुरू की गयी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम क्या रूप लेती है। इस बारे में कुछ और कहना उन्हें जल्दबाजी लगती है।

—अटल बिहारी शर्मा

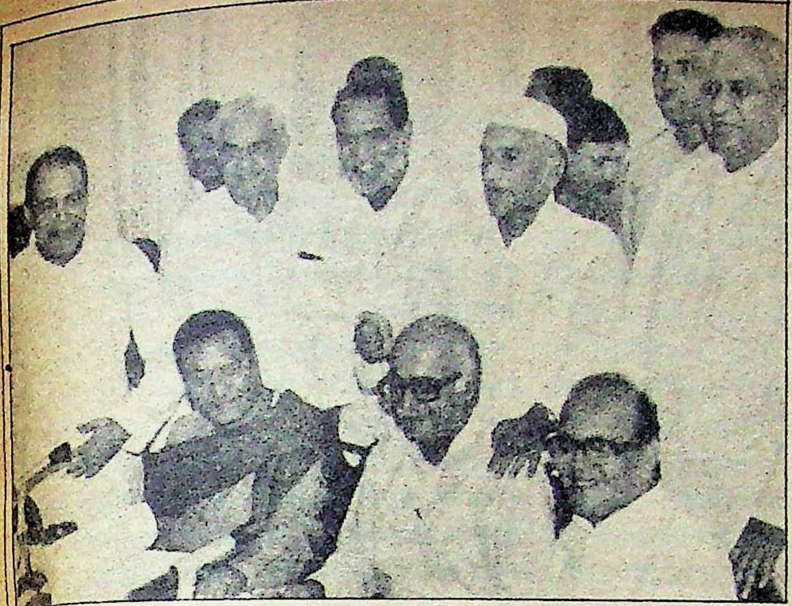

निर्विकल्प विपक्ष

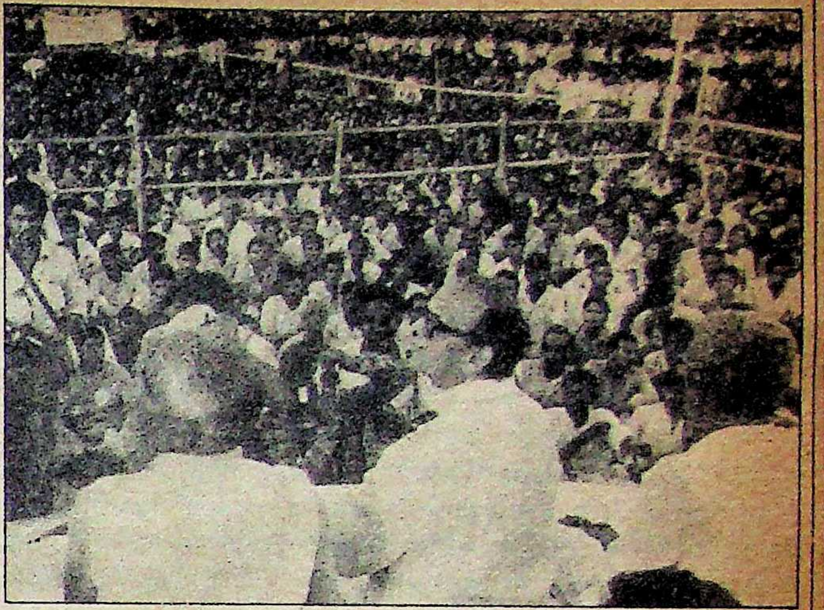

भविष्य दांव पर

में अचानक महंगे हुए आलू-प्याज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों प्याज-आलू से भरी गाड़ियां सप्ताह में दो बार उपभोक्ताओं को बाजार से लगभग दो तिहाई कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का उपक्रम जोर-शोर से जारी है। इसे भी जनता-जनार्दन के कष्ट निवारण के प्रयास के अतिरिक्त चुनाव को मद्देनजर रख, मन जीतने का एक आजमाया हुआ तरीका माना जा रहा है।

मध्यावधि चुनाव के संकेतों की दुरबीन खोज करने वालों को बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की कछुआ चाल के पीछे भी मध्यावधि चुनाव दिखायी पड़ रहा है। सूत्रों का विचार है कि समिति की रिपोर्ट ठीक चुनाव के पूर्व आयेगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी दूध के धुले निकलेंगे और उनकी इस छवि का चुनाव में लाभ उठाया जायेगा। समिति की धीमी गति का यही कारण आंका जा रहा है।

यद्यपि इन संकेतों का खंडन यदाकदा कांग्रेसी खेमे से हुआ है। वैसे तो स्वयं प्रधानमंत्री व उनके कुछ वरिष्ठ सहयोगियों ने एक-आध बार चुनाव की संभावना से इनकार किया है, किंतु प्रसिद्ध राजनीतिक पर्यवेक्षक भवानी सेन गुप्त प्रधानमंत्री के स्वर और बीच-बीच में उनकी खामोशी को 'अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति' मानते हैं। पूर्ण स्वीकारोक्ति हो या नहीं, यह इस बात का द्योतक अवश्य है कि शासक दल में चुनाव संबंधी विचार-विमर्श अवश्य चल रहा है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुछ जाने-माने राजनीतिक पर्यवेक्षक और उच्चकोटि के चुनाव विशेषज्ञों को भी हवा के रुख का हवाला देने का काम सौंपा गया है। अतः सभी दरवाजे अभी भी खुले रखे गये हैं, इसमें संदेह नहीं है।

कांग्रेस की राज्य इकाइयों से भी इस संबंध में राय मांगी गयी थी। यद्यपि अधिकांश ने दबे स्वरों में इससे असहमति व्यक्त की है, किंतु सभी ने आलाकमान के निर्णय को शिरोधार्य करने की बात भी कही है। वैसे मत यही है कि चुनाव के लिए फिलहाल समय अपरिपक्व है।

अपरिपक्व समय: मध्यावधि चुनाव की लगातार मांग करने वाले सभी विपक्षी दल कांग्रेस के लिए समय की अपरिपक्वता को स्वीकारते हैं। जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने 'माया' से कहा, "राजीव गांधी स्वयं यह खतरा कतई मोल नहीं लेंगे। पिछले तीन वर्षों में उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की है। हां, प्रबल जनमत के दबाव में उन्हें मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।"

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव एम० फारूकी भी मध्यावधि चुनाव की संभावना के प्रति संदेह प्रकट करते हैं, "अधिकांश कांग्रेसी सांसद यह जानते हैं कि चुनाव में हार निश्चित है, अतः वे कभी भी मध्यावधि चुनाव के लिए राजी नहीं होंगे। हां, यदि कोई बड़ी घटना राजीव गांधी अथवा पार्टी के पक्ष में घटित हो जाये, तो बात दूसरी है।" इससे ठीक विपरीत मत लोकदल—अ के सुब्रह्मण्यम स्वामी का है, जिनका यह मानना है, "जिस प्रधानमंत्री की हार निश्चित हो, वह तभी चुनाव करायेगा, जब उसका कोई और बस न चले। जैसे यदि बोफोर्स काण्ड में कुछ ऐसे नाम निकल आयें, जिसके बाद सरकार का गद्दी पर टिके रहना असंभव हो जाये।"

अभी तक दो बार अचानक चुनाव हुए हैं। एक बार १९७१ में और दूसरी बार १९७७ में। १९७१ के पहले श्रीमती गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त कर और 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर अपनी अच्छी-खासी छवि बना ली थी, जिसका उन्हें १९७१ के चुनावों में फायदा मिला। १९७७ में श्रीमती गांधी ने अचानक चुनावों की घोषणा की थी। उन्हें लगा था कि इमरजेंसी के कारण उनकी छवि काफी धूमिल हो रही है और आगे और हो सकती है। इसलिए वह इससे पहले कि मामला और बिगड़े और विपक्ष को चुनाव की तैयारी करने का मौका मिले उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी, लेकिन नतीजा हुआ श्रीमती गांधी की पार्टी का सफाया।

आज भी कुछ लोग यही तर्क देते हैं कि इससे पहले कि घोटालों आदि के कारण राजीव गांधी की छवि और धूमिल हो, उन्हें मध्यावधि चुनाव करा लेना चाहिए। नहीं तो उनकी गिरती छवि से चिंतित होकर कांग्रेसी उनसे दामन छुड़ाना शुरू कर देंगे।

कांग्रेसी चरित्र की चर्चा करते हुए सोमनाथ चटर्जी ने बताया, "जिस दिन कांग्रेसियों को यह विश्वास हो जायेगा कि राजीव गांधी का साथ देने में उनकी खैर नहीं, उस दिन वे उन्हें धता बता देने में न देर करेंगे न संकोच। अतः राजीव के नेतृत्व को मिली कोई भी चुनौती उन्हें चुनाव की घोषणा कराने के लिए उकता सकती है।"

राजीव गांधी के नेतृत्व को कोई खतरा है, इससे अधिकांश कांग्रेसी कम-से-कम सार्वजनिक रूप में असहमति जताते हैं। पार्टी सांसद और बोफोर्स जांच समिति के सदस्य थंगाबालू कहते हैं कि देश के सभी पार्टी सांसद, विधायक, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूर्ण रूप से राजीव गांधी के प्रति एकनिष्ठ और समर्पित हैं। उनके अतिरिक्त समस्त देश में सर्वस्वीकृत नेता है ही कौन? यह तो कुछ स्वार्थी, और अपना उल्लू सीधा करने वाले विदेशी एजेंट—जैसे वी०पी० सिंह और उनके गुट के लोग हैं, जिन्होंने गद्दारी की है।"

भगदड़ को रोकने के प्रयास: इस समर्पण और एकनिष्ठा का प्रमुख कारण है दलबदल विरोधी कानून। यदि यह कानून न बना होता, तो कहा नहीं जा सकता कि कितने सांसद और विधायक कांग्रेस के झंडे तले बने रहते। राजीव गांधी का दामन पकड़े रहने का एक अन्य कारण यह भी माना जाता है कि ज्यादातर सांसद और विधायक पहली बार चुनकर आये हैं। उनको पेंशन और भत्ता पाने के लिए आवश्यक है कि वह ५ साल की अवधि पूरी करें। इसलिए मध्यावधि चुनाव का सबसे मुखर विरोध इन्हीं लोगों से अपेक्षित है। कारण एक तो यह कि पेंशन भत्ता मारा जायेगा। दूसरा, आगे टिकट

मिलेगा या नहीं और यदि मिल भी गया, तो चुने भी जायेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए चन्द्रशेखर मानते हैं, "यह निर्वाचित कांग्रेसी भी मध्यावधि चुनाव कराना पसंद नहीं करेंगे। यदि राजीव गांधी ऐसा करते हैं, तो वे सब-के-सब उन्हें छोड़ जायेंगे।"

इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए राजीव गांधी संसद के वर्तमान सत्र में एक ऐसा विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत यदि संसद ५ वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले मध्यावधि चुनाव के लिए भंग कर दी जाती है, तो सदस्यों की पेंशन और भत्ते पर आंच नहीं आयेगी। इस विधेयक द्वारा सांसदों को खुश रखने के प्रयास से मध्यावधि चुनाव की संभावना के लक्षण और उजागर हो जाते हैं। राजीव गांधी परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए दोनों दरवाजे खुले रखने की सोची-समझी सफल नीति का प्रयोग कर पार्टी से पलायन करने वालों की बाढ़ को रोक रहे हैं।

राजीव गांधी की इन तमाम कसरतों के बावजूद पार्टी के भीतर-बाहर असंतोष और संशय अभी भी पूरी तरह व्याप्त है। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह कहते हैं—"अपनी प्रचंड सफलता के दो वर्ष के अंदर ही राजीव गांधी वोट बटोरने वाले से वोट गंवाने वाले में बदल गये। वह कांग्रेस को सत्ता में बनाये रखने में जहां शुरू-शुरू में बहुमूल्य पूंजी साबित हुए थे, वहीं अब सबसे बड़े बाधा बन गये हैं। उनके डूबते जहाज को छोड़कर जाने वाले चूहे नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्वास हो गया था कि सफर जारी रखने की एकमात्र शर्त है कि 'पायलट' को बदल दिया जाये।"

मध्यावधि चुनाव के होने की संभावना को क्षीण मानते हुए भी लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल इसकी मांग को दोहराते जा रहे हैं। 'माया' से इस विषय पर अनौपचारिक बातचीत में लोकदल-ब अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा नैतिकता का प्रश्न उठाकर कहते हैं, "देशभक्ति और लोकतंत्र का तकाजा है कि राजीव गांधी पुन: जनादेश प्राप्त करें। संसद के भीतर का बहुमत बाहर के व्यापक जनमत के बिलकुल विपरीत है। मैं यदि राजीव गांधी की जगह होता, तो जनमत को देखते हुए निश्चय ही मध्यावधि चुनाव कराता। समूचा शासन तंत्र लुंज-पुंज हो गया है, जिसके कारण देश का हर छोटा-बड़ा काम आधा-अधूरा पड़ा है। भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोपों की गिरफ्त में फंसी सरकार ही नहीं, समूची कांग्रेस पार्टी इस समय कटघरे में खड़ी है। चुनाव संबंधी उनका निर्णय यह सिद्ध करेगा कि उनका सरोकार राष्ट्रहित से है अथवा स्वहित और पार्टी हित से।"

सरकार के इसी नकारापन को उजागर करते हुए भूतपूर्व आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री और जनमोर्चा नेता अरुण नेहरू ने 'माया' से कहा, "राजीव गांधी आज अपने अनिर्णयों के दायरे में जिस बुरी तरह घिरे हुए हैं, उससे उनका दो साल पूरा कर पाना बेहद मुश्किल है। काम करने वाली सरकार का यह हाल है कि मंत्रिमंडल में जरूरी फेरबदल तो दरकिनार, देश के सर्वाधिक बड़े व प्रमुख २४ सार्वजनिक संस्थान जिनमें भेल, एनटीपीसी, एमएमटीसी, एसटीसी शामिल हैं, बिना अध्यक्षों के भगवान भरोसे चल रहे हैं। अनिर्णय की यह स्थिति सरकार के सभी अहम कामकाजों में बाधक है। ऐसी स्थिति में खोयी विश्वसनीयता प्राप्त करने और पूरे देश में आस्था, विश्वास और सक्रियता का माहौल पुन: बनाने के लिए मध्यावधि

आर्थिक क्षेत्र में: इच्छा या अनिवार्यता!

चंद उन अहम आर्थिक समाचार टिप्पणियों पर नजर डालें, जिन्होंने गत नवंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बहुतों को उत्तेजित-उद्वेलित कर दिया—कम से कम १००० करोड़ रु० के अतिरिक्त साधनों की कमी, राष्ट्रीय आय बढ़ोत्तरी की दर वर्तमान वित्तीय वर्ष में शून्य, मौजूदा कृषि वर्ष की पैदावार में गत वर्ष की तुलना में कम से कम १० प्रतिशत की गिरावट, आर्थिक क्षेत्र में मांग में चौमुखी मंदी से व्यवसायियों में भारी घबराहट, अतिरिक्त पूंजी निवेश उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि नये रोजगार उपलब्ध कराने के लिये खासकर सरकार के वे विशेष कार्यक्रम जो उत्पादन में उतने सहायक नहीं जितने असंख्य लोगों को रोजगार देने में, विश्व बैंक के अध्यक्ष कोनबेल का यह कथन कि विश्व बैंक ने भारत को ३५ करोड़ डालर देने का फैसला किया और ३५ करोड़ का एक नया कर्ज भारत को देने पर विचार, सरकार द्वारा अभूतपूर्व सूखे से उत्पन्न किल्लत को देखते हुए भारी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात।

इस सबको मद्देनजर रखते हुए भलीभांति समझा जा सकता है कि कैसा असंतोष पिछले कुछ महीनों में खदबदा रहा है। डाक्टर, इंजीनियर, सी०पी०डब्ल्यू०डी० कर्मचारी, स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षक और उ०प्र० सहित कुछ अन्य राज्यों के कर्मचारी हड़ताल के मैदान में उतर आये या इसकी धमकी दी। वामपंथी पार्टियां मजदूरों की छंटनी से होने वाली व्यापक बेरोजगारी, मंहगाई आदि के खिलाफ कारखाना मजदूरों की नयी दिल्ली में विशाल रैली निकालने के लिए पूरे जोरशोर से जुटी हैं। थोक मूल्य सूचकांक में अक्तूबर से प्रारंभ अवधि की सामान्य मौसमी गिरावट का उलटा हुआ। पिछले छह महीनों में मूल्यों में कहीं अधिक वृद्धि हुई। खासकर आवश्यक जिन्सों के मामले में। शेयर बाजार में उदासी छायी है और सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों—मसलन यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया व जीवन बीमा निगम के सभी प्रयास नाकाम साबित हुए हैं।

अब सवाल यह उठता है, राजीव के लिए चुनाव कराना फरवरी-मार्च १९८८ में उचित होगा या १९९० में? पहली प्रतिक्रिया 'नहीं' में ही होगी। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोग संगठित रूप से रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे असंतुष्ट व अशांत लोगों से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि उनका निर्णय प्रधानमंत्री व शासक दल के पक्ष में होगा?

किंतु साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि क्या यह उम्मीद करने की पर्याप्त वजह है कि अभी और १९९० के बीच, जबकि सामान्य चुनाव होने हैं, स्थिति सुधरेगी? और शायद पिछले कुछ महीनों के दौरान यह सवाल पहले सवाल से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही एक नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसने चुनाव निर्णय के संबंध में ईश्वरीय वरदान के साथ-साथ एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है। सूखे ने कम से कम सात राज्यों के, जहां लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटें हैं, बहुसंख्यक लोगों और मतदाताओं को सीधे-सीधे प्रभावित किया है। यह 'ईश्वरीय वरदान' है, क्योंकि यदि सूखा राहत कोष का थोड़ा-सा अंश भी कुछ लोगों को मजदूरी, अनाज, पीने का पानी, कृषि पैदावार के लिए मुफ्त या सस्ती खाद के रूप में भेजा जाता है, तो वे लोग प्रधानमंत्री व उनकी सरकार को अपना अन्नदाता समझने लगते हैं। ऐसे में वोट प्राप्ति की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए।

पर यह एक गंभीर समस्या भी है। खासकर इसलिए कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही मांग की मंदी का शिकार है और देशी व विदेशी पूंजी निवेशक अनिश्चय की भावना से ग्रस्त हैं। क्रूर प्राकृतिक विपदाओं की मार से एक गहरी खायी में ढकेल दी गयी है। कीमतों में सूखे के कारण कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सरकारी सूखा राहत से लाभान्वित होने वाले खुशी महसूस करेंगे, किंतु जो लोग दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति, बढ़ती बेरोजगारी (जिसका कारण है शोचनीय अर्थव्यवस्था) और बढ़े हुए करों से प्रभावित हैं वह शासक दल के प्रति उदारता नहीं बरतने जा रहे हैं। चावल, गेहूं, सब्जी, खाद्य तेल और कपड़े—ये सभी चीजें लगातार मंहगी

चुनाव आवश्यक है।"

राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजीव गांधी को अप्रत्यक्ष सहयोग देकर बचाने वाले वामपंथी दल भी इस समय मध्यावधि चुनाव का जोरदार नारा बुलंद कर रहे हैं। भाकपा सचिव फारूकी इस बदले रुख को मौकापरस्ती न कहकर लोकतांत्रिक प्रणाली में अटूट आस्था का परिचायक बताते हैं। उनके अनुसार, "यह एक सैद्धांतिक मुद्दा है। सन् ८४ की अभूतपूर्व विजय के बाद राजीव गांधी को लगभग सभी चुनावों में पराजय प्राप्त हुई है जो देश की मनोदशा को स्पष्ट करती है। अतः पुनः मतदाताओं के पास जाना आज उनके लिए अनिवार्य बन गया है।" के०पी० उन्नीकृष्णन तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वह कहते हैं कि यदि राजीव गांधी सच्चे लोकतांत्रिक होते और जनता की नब्ज से वाकिफ होते, तो पिछले बजट सत्र के बाद ही वह संसद को भंग कर पुनः चुनाव कराते, किंतु मुझे शक है कि मध्यावधि चुनाव कराये जायेंगे।

उन्नीकृष्णन के अनुसार, "साधारणतया मध्यावधि चुनाव दो परिस्थितियों में कराये जाते हैं। अपनी विजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त नेता अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए। दूसरे, संदेहों के घेरे में घिरा नेता, जिसे अपनी सफलता के लिए दोनों ही परिस्थितियों में हार निश्चित है। वह चुनाव सन् ८८ में करायें या ८९ में अपनी ८४ वाली ऐतिहासिक सफलता, जिसके कारण कुछ अन्य ही थे, को कभी भी दोहरा नहीं पायेंगे।"

अफवाह फैलाने का आरोप : समस्त विवादों के बीच विचाराधीन बात यह है कि चुनाव की अफवाह फैलाने का दोषारोपण सीधे-सीधे भाजपा पर डाला जा रहा हैं। कहा जाता है कि विपक्ष में भी अलग-थलग पड़ गयी भाजपा मध्यावधि चुनाव के लिए कतई तैयार नहीं है। इसलिए अफवाह फैलाकर चुनाव की रही-सही संभावना को समाप्त करना ही उसका उद्देश्य है। ऐसे 'बेबुनियाद' आरोपों के कारण भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी का क्रुद्ध होना नितान्त स्वाभाविक है, "ऐसी अफवाह फैलाने का प्रश्न ही कहां उठता है? हमने तो हमेशा यही कहा है कि राजीव गांधी मध्यावधि चुनाव कभी नहीं करायेंगे। किंतु हम यह जानते हैं कि सत्ताधारी दल में एक गुट अवश्य है, जिसका कहना है कि कल स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसी विचारधारा के तहत वह चुनाव का जुआ खेलें, तो खेलें अन्यथा कांग्रेस के लिए वातावरण प्रतिकूल ही है।"

इसके ठीक विपरीत मत है भवानी सेन गुप्त का, जिनका यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में सफलता हासिल करने की पूरी संभावना है जिसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

विपक्ष इस समय अलग-थलग और विभाजित है। अतः उसे चुनाव मैदान में पछाड़ना आसान होगा।

विश्वनाथ प्रताप सिंह अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर राजीव गांधी का विकल्प बनने में असमर्थ रहे हैं। अधिक समय मिलने पर वह इस कमी को पूरा करने में सफल हो सकते हैं।

बोफोर्स आदि विवादों के कारण लगातार गिरती हुई साख को राजीव गांधी रोकने में सफल हुए हैं। उनके ऊपर मंडराते बादल फिलहाल कुछ छंट गये हैं।

पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में सरकार पहले की अपेक्षा अधिक सफल हुई है और हिंसक गतिविधियों की रोकथाम कर सकी है।

सूखे और श्रीलंका के तहत बढ़े खर्चे का दुष्प्रभाव अगले वर्ष अधिक जान पड़ेगा। यदि अगला वर्ष भी

होती जा रही हैं। कोई भी दलील सहित भरोसा नहीं दिला सकता कि तीव्र रफ्तार की यह मूल्यवृद्धि शीघ्र थम जायेगी। इसके उलटे हर जानकार व्यक्ति और संस्थान यह कह रहा है कि यह ऐसी भयंकर मुद्रास्फीति का वर्ष साबित होने जा रहा है, जिसका देश ने गत ११ वर्षों में कभी सामना नहीं किया होगा।

चुनावों में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है—मूल्यों और करों का। पहली चीज हरेक को प्रभावित करती है, भले ही आमदनी का स्तर कुछ भी हो। दूसरी चीज प्रत्यक्ष रूप में उन्हें प्रभावित करती है जो निजी आयकर, संपत्ति कर, व्यवसाय लाभ कर या अन्य प्रत्यक्ष कर अदा करते हैं। प्रत्यक्ष करों में पहले ही कुछ बढ़ोत्तरी के आदेश हो चुके हैं और कुछ रेल किरायों में भी वृद्धि की गयी है। सरकार जिस १००० करोड़ रु० के साधनों की कमी की चर्चा कर रही है, उसका मतलब है अतिरिक्त करों, तटकर और उत्पाद शुल्कों, आय व संपत्ति करों के द्वारा अधिक धन उगाही की भूमि तैयार करना। यदि आज या कल यह कदम उठाया जाता है, तो उदार कर प्रणाली की आशा संजोने वालों को निश्चय ही निराशा का सामना करना पड़ेगा। किंतु अलोकप्रिय वित्तीय कदमों को चंद महीने स्थगित रखना कोई नामुमकिन नहीं है। अधिक संभावना इसी बात की है कि आम चुनाव कराने के बाद कर बढ़ाये जायेंगे।

इसी प्रकार कम से कम कुछ महीने मूल्यवृद्धि के प्रभावों को कम करना भी संभव है। इस मामले में विश्व बैंक का कर्ज मददगार साबित होगा। विश्व बैंक से विदेशी मुद्रा का अंधाधुंध कर्ज और आम इस्तेमाल की कम सप्लाई वाली जरूरी जिन्सों की खरीद में हर्ज ही क्या है? यह जरूर है कि हर कर्ज का लाजिमी असर होता है। उसे चुकता करना पड़ता है, ब्याज अदा करना पड़ता है और मूल रकम तथा वार्षिक किस्त की अदायगी में देरी की सूरत में देनदारी लगातार बढ़ती जाती है। पर हर असहाय कर्जदार की तरह हमेशा यह खयाली मंसूबा पाला जा सकता है कि कल खुशहाली का दिन आयेगा।

इसके अलावा कुछ गंभीर मुद्दे हैं। कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। भारी मुश्किल तब दरपेश होती है जब अदायगी का समय आता है। इस तर्क से १९८८ के शुरुआती महीनों की अपेक्षा १९९० बदतरीन समय सिद्ध होगा। बशर्ते निर्यात के मोर्चे पर देश की भूमिका सहसा बेहतरीन न बन जाये। किंतु यह किसी चमत्कार की आशा करने के समान होगा और राजीव गांधी को यह अहसास जरूर होगा कि चमत्कार कभी नहीं होते, भले ही ज्योतिषी उसकी भविष्यवाणी करते रहें। साथ ही राजीव के दोस्त—यदि वे सचमुच के दोस्त और समझदार लोग हैं, तो—उन्हें बतायेंगे कि सूखे का अगले वर्ष पड़ने वाला असर किसी मायने में इस वर्ष से बेहतर नहीं होगा। बिजली उत्पादन में कमी की विकटता का अहसास अगली गर्मी में होगा और लगभग समान किल्लत उसके बाद की गर्मी में उठानी पड़ेगी। शहरी बिजली उपभोक्ताओं को उन्हीं दुःस्वप्नों से गुजरना होगा, जिनसे दिल्लीवासी और अन्य महानगरों के लोग इस गर्मी में गुजरे थे। उत्तर भारत में उद्योग, कृषि और घरेलू क्षेत्र तब एक-दूसरे को कोसेंगे जब एक की बिजली रोक कर दूसरे को दी जायेगी।

सतह के पानी से की जाने वाली सिंचाई का अगले वर्ष बुरा हाल होगा। वर्षा छिटपुट होने और पहाड़ों पर अपेक्षाकृत कम पानी एकत्र होने से सिंचाई की संभावना बहुत कम हो जायेगी। इसके परिणामों की कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

नतीजतन फसलें प्रभावित होंगी—खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां रबी मुख्य फसल होती है। अधिकाधिक राहत मुहैया कराने की मांग हर सूरत में बढ़ती जायेगी और सरकार के वित्तीय तरकश के तीर और ज्यादा होंगे, क्योंकि आय राजस्व वित्त मंत्रालय के नौकरशाहों के आदेशों और प्रधानमंत्री व खुद वित्त मंत्री की सनकों से निरंतर बढ़ाया नहीं जा सकता।

फिर चारा क्या है? अपनी इच्छा पर अड़े रहकर इस सवाल में उलझे रहना कि १९८८ की अपेक्षा १९९० अधिक शुभ होगा? अथवा यह क्रूर सत्य मान लेना क्या अक्लमंदी होगी कि राजनीति में चुनावों का इस्तेमाल केवल लचीलेपन से संबंधित अनिवार्यताओं के एक पेश ढांचे में किया जाता है? राजीव गांधी निसंदेह चुनाव करने की स्थिति में हैं, किंतु अपरिहार्य आर्थिक सचाई की अनिवार्यताओं के भीतर रहकर ही यह सब उनके विवेक पर निर्भर करता है। बहरहाल, दीवार पर लिखी इबारत साफ-साफ मध्यावधि चुनाव के फैसले का संकेत करती है।

—कुमारेश चक्रवर्ती

मतदाता की राय

मध्यावधि चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों के बीच चल रहे विचार-विमर्श में यदि किसी एक तबके की अवहेलना की जा रही है, तो वह है स्वयं मतदाता। प्रस्तुत है 'माया' की विशेष टीम द्वारा एकत्र जनता की प्रतिक्रियाएं:

राजीव गांधी के अस्तित्व के लिए क्या कोई संकट आपको दीख रहा है कि मजबूरी में वह त्याग पत्र देकर चुनाव करवायें? अगर कांग्रेसी सांसद भी उनसे किनारा कस लें, जो सर्वथा असंभव है, तो वह इमरजेंसी लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। फिर भी मुझे न तो इसकी संभावना दीख रही है और न ही आशा, क्योंकि विपक्षी नेताओं के पास सिवाय सरकार और प्रधानमंत्री को कोसने के कोई और काम ही नहीं है। जब तक वे आम जनता की मूल तकलीफों-समस्याओं को दूर करने के लिए उसका विश्वास नहीं प्राप्त करेंगे, आम जनता उनके साथ नहीं रहेगी। सिर्फ रैलियों में भीड़ बटोरने से जन-समर्थन नहीं मिल जाता।—*एस० उषा (प्राध्यापिका, उम्र ४० वर्ष), बंबई*

प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्या पड़ी है कि वह इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव करायें और जोखिम मोल लें। फिर कौन सी पार्टी या नेता है जो उनकी जगह ले सकता है? —*सुरेश दत्तात्रेय सावंत, (कंपनी एक्जीक्यूटिव, ३५ वर्ष) बंबई*

आज देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव एक बहुत महंगा खर्च होगा और वैसे भी विपक्षी दल संगठित नहीं हैं।—*राजेश नरूला, २७ वर्ष, विद्यार्थी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली*

प्रधानमंत्री ने भला क्या गुनाह किया है कि वह इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव करायें।—*डिंपी कपूर, (मॉडल, १९ वर्ष) बंबई*

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव कराने की बात तो तब आती जब बोफोर्स दलाली का आरोप सीधा उन पर लगाया गया होता और वह दोषी सिद्ध होते।—*जानकी दास, (चरित्र अभिनेता, ६० वर्ष) बंबई*

इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि राजीव मध्यावधि चुनाव कराते हैं या नहीं या फिर सत्ता में कौन है, कौन नहीं है? सभी राजनीतिज्ञ एक समान हैं। हमारे विरोधी दलों के नेताओं सहित ये सभी राजनीतिज्ञ होटलों में बैठे मद्यपान में व्यस्त रहते हैं।—*गुरचरण सिंह, दसवीं कक्षा का छात्र, खिलाड़ी, दिल्ली*

वह (राजीव गांधी) प्रधानमंत्री होने के योग्य नहीं है। नये चुनाव कराये जाने चाहिए। जिससे कि एक नयी सरकार केन्द्र में आ सके। राजीव शासन के तीन साल बहुत हैं।—*राम प्रसाद, साइकिल मैकेनिक, दिल्ली*

मेरे विचार से राजीव को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पहले ही अपने आपको जनता के समक्ष साबित करने के लिए पांच साल का समय दिया गया है। वैसे मैं समझता हूं कि यदि इस समय मध्यावधि चुनाव कराये जाते हैं, तो वह (राजीव) चुनाव हार जायेंगे। —*बी०के० वर्मा, २८ वर्ष, घड़ीसाज, दिल्ली*

मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पर मध्यावधि चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता है। इससे देश को करोड़ों रुपए का खर्चा वहन करना पड़ेगा जबकि दूसरी ओर हम भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। केवल इस (बोफोर्स) कांड में शामिल व्यक्तियों का नाम बताकर ही देश की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित की जा सकती है।—*डा० आदित्य प्रसाद मिश्रा, ३० वर्ष, चिकित्सक, भुवनेश्वर, उड़ीसा*

चूंकि अनेक देशवासियों के मन में श्री गांधी की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव कराने चाहिए जिससे कि जनता के मन में उनके प्रति विश्वास जगाया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री को सभी प्रकार के संदेहों से परे होना चाहिए। —*सुभाष चन्द्र आपात, २१ वर्ष, एक निजी प्रतिष्ठान में चपरासी, भुवनेश्वर, उड़ीसा*

राजीव गांधी को चाहिए कि वह इस्तीफा देकर चुनाव करायें जिससे पता चलेगा कि जनमत उनके साथ है या नहीं। अगर चुनाव में राजीव दुबारा जीतते हैं, तो साबित हो जायेगा कि जनता राजीव को दोषी नहीं मानती। —*डा० शिशुपाल राम, पटना, बिहार*

सूखे या बाढ़ की चपेट में आ गया, तो आर्थिक परिस्थितियां और गंभीर रूप धारण कर लेंगी, जिनमें निपटना किसी भी सरकार के लिए बहुत कठिन होगा।

अपनी दलील में वह आगे कहते हैं, "आज की परिस्थिति सन् ६७-६८ की याद ताजा कर देती है। छठे दशक के उत्तरार्द्ध मे बिहार का अकाल, सूखा और रुपए के अवमूल्यन के कारण समूचा उत्तर भारत श्रीमती गांधी के हाथ से निकल गया था। राजीव गांधी के लिए यही बेहतर होगा कि परिस्थितियां बेकाबू होने से पहले वह मध्यावधि चुनाव करा लें।"

विपक्ष अपने असंगठित होने के आरोप से इनकार करता है। उसका दावा है कि बहु पार्टी प्रणाली में प्रत्येक दल का अपने विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करना अस्वाभाविक नहीं। ऐतिहासिक अनिवार्यताओं की स्थिति में आपसी मतभेद भुलाकर कुछ विशिष्ट मुद्दों को लेकर एकजुट होना कोई कठिन काम नहीं है। सुब्रह्मण्यम स्वामी इस मुद्दे को निरर्थक करार देते हुए कहते हैं—"आवश्यकता पड़ने पर विपक्ष रातोरात एकजुट हो जायेगा। इसके लिए समस्त प्रारंभिक तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं।"

उन्नीकृष्णन कहते हैं कि संसार में कहीं भी सभी विपक्षी दल संयुक्त रूप से चुनाव नहीं लड़ते। यह 'मीडिया' द्वारा प्रसारित और मध्यवर्ग द्वारा प्रचारित एक 'मिथ' है। विपक्ष देश में आज एकजुट हो जाये, यह व्यापक जनाकांक्षा विद्यमान है। वैसे भी जनता पार्टी और सरकार की असफलता ने सभी दलों को फूट के दुष्परिणामों का सबक भलीभांति सिखा दिया है।

मध्यावधि चुनाव का कट्टर विरोध करनेवालों का प्रमुख तर्क है कि इस अनावश्यक कार्य में राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ती है—धन के रूप मे, शक्ति के रूप में, साधन के रूप में। उनका यह भी मानना है कि विभिन्न राष्ट्रीय संकटों जैसे सूखा, मूल्यवृद्धि, साम्प्रदायिकता और अलगाववादी मसलों मे निपटने की जगह समूची राष्ट्रीय शक्ति का यह दुरुपयोग किस काम का ? विशेषकर तब, जबकि चुनकर आने वाले न्यूनाधिक रूप में इसी थैली के चट्टे-बट्टे होंगे। वैसे भी भ्रष्टाचार का केवल कांग्रेस से ही नाता नहीं है। धन शक्ति के बिना लोकतत्र की कल्पना मात्र कल्पना ही रहेगी।

इस विचार से कोई भी विपक्षी नेता सहमत नहीं। सभी का यह कहना है कि चुनाव के मद में होने वाला २०० करोड़ रुपए का यह खर्च कतई बेमानी नहीं है। "अकेले श्रीलंका के विफल अभियान में—क्योंकि सुरंग के अन्त में भी कहीं रोशनी की किरण नजर नही आती—लगभग २००० करोड़ पर पानी फिर जाने वाला है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया २०० करोड़ का अपेक्षाकृत अल्पव्यय पूर्णतया समुचित है," बहुगुणा कहते हैं।

व्यय के अतिरिक्त दूसरा अहम सवाल है चुनाव संबंधी देशव्यापी तैयारियां, क्योंकि मात्र विचारों से ही चुनाव संपन्न नहीं होते। इसके लिए पर्याप्त समय नितान्त आवश्यक है। निर्वाचन आयोग के एक सूत्र के अनुसार यदि चुनाव की घोषणा ३१ दिसंबर से पहले नहीं की जाती, तो संपूर्ण मतदाता सूचियों के संशोधन के कार्य में बाधा पड़ेगी। कारण इसमें लगभग एक माह का समय कम-से-कम जरूरी होता है। उसके बाद ही चुनाव अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस अधिसूचना और मतदान के मध्य भी ४-५ सप्ताह के समय की आवश्यकता होती है। इन्हीं प्रशासनिक कार्यवाहियों के कारण अटकल लगायी जा रही है कि यदि मध्यावधि चुनाव हुआ भी, तो वह मार्च १९८८ के आसपास ही होगा। कुछ चुनाव पंडित तो तारीख तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखना यही है कि उनकी १० मार्च की भविष्यवाणी सही उतरती है या नहीं।

प्रश्न अब यही उठता है कि क्या मध्यावधि चुनाव सचमुच होगा ? इस संबंध में 'माया' से एक विशेष भेंट में बहुगुणा ने कहा, "इस संबंध में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना कठिन है। कांग्रेस आज अराजनीतिक लोगों की एक दिग्भ्रमित भीड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अत: इन लोगों की कथनी करनी के बारे में कुछ भी कह पाना सर्वथा असंभव है। यदि डर है, तो राजभक्तों का। यदि उनकी चली, तो मध्यावधि चुनाव न होगा, देशभक्तों की चली, तो अवश्य होगा।"

इस अनिर्णायक स्थिति का दोषी, लालकृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी को ठहराते हैं, "राजीव गांधी की न तो कोई व्यवस्थित, विधिवत, सोची-समझी कार्यशैली है, न ही कोई पूर्व निर्धारित योजना। और-तो-और उनको यह पता नहीं कि आज क्या करेंगे और कल क्या करेंगे।"

उमाशंकर दीक्षित को जो संगठन संबंधी कार्य सौंपा गया है, उसके विषय में सत्ता गलियारों में चर्चा है कि उनको चुनाव-परिणामों को आंकने और

मध्यावधि चुनाव और ज्योतिष

सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में तंत्र-मंत्र और ज्योतिष का बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण हाथ रहा है। जवाहर लाल नेहरू को छोड़ भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई अन्य राजनीतिज्ञ नहीं हुआ, जो समय-असमय इस संक्रामक रोग का शिकार न हुआ हो। पाश्चात्य जीवन शैली में रची-बसी इन्दिरा गांधी भी इससे अछूती नहीं रहीं थीं। उनके लम्बे शासन काल के दौरान हुए अनगिनत यज्ञ अपने तामझाम के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे।

राजीव गांधी का शासनकाल कुछ भिन्न नहीं है। आधुनिकता के रंग में पूर्णतया रंगे और २१वीं शताब्दी में जाने के लिए आतुर राजीव गांधी प्रत्यक्ष रूप में भले ही इन आडम्बरों से दूर दिखायी पड़ते हों, किंतु अपनी छवि बनाने के लिए वह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का न केवल कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, वरन उनमें विश्वास भी रखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के एक कांग्रेसी सांसद के घर में राजीव गांधी के कल्याण हेतु आयोजित १४ दिन लम्बे यज्ञ में जिस भक्तिभाव से वह सम्मिलित हुए, वह कर्मकाण्ड में उनकी बढ़ती आस्था का द्योतक है।

कुंडलियां—चाहे वह राष्ट्र की हों या राष्ट्र नायक की—यदा-कदा खोली और पढ़ी जाती रही हैं। उनका प्रभाव प्राय: देश के अनेक छोटे-बड़े मुद्दों में निर्णायक सिद्ध हुआ है। आज भी वातावरण कुछ इस प्रकार बन गया है कि राष्ट्र और राजीव की कुंडलियां बांची जा रही हैं।

कुछ समय पहले एक उच्च पार्टी के पदाधिकारी और सांसद कुछ उदास, खिन्न और मुंह लटकाये पाये गये। कारण पूछने पर पता चला कि उन्होंने राजीव गांधी की जन्मकुंडली को दिखाया था। पंडितों की भविष्यवाणी थी कि गत अगस्त माह से उनकी (राजीव गांधी) ग्रहदशा बिगड़ गयी है। यह सांसद बोफोर्स पनडुब्बियां आदि काण्डों द्वारा राजीव की धूमिल होती छवि के पीछे इसी ग्रहों के फेर का हाथ बता रहे थे। ग्रहों की शांति निवारण की खोज में तल्लीन यह सांसद अन्य सभी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने में कोई हानि नहीं समझ रहे थे। कदाचित उन्हीं के प्रयासों का फल है कि राजीव गांधी के ऊपर घिरे संकटों के बादल कुछ कम हुए हैं।

देश और राजीव कल्याण की चिंता केवल इन्हीं सांसद को नहीं है। कांग्रेसियों में इस संबंध में पहल के लिए हमेशा होड़ लगी रहती है। चालू संसद सत्र के दौरान संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में चर्चा का मुख्य विषय राष्ट्र और राजीव की वर्तमान ग्रहदशा थी। वहां मालूम हुआ कि फिलहाल ग्रह अनुकूल हैं और मार्च के अंत तक यह कृपादृष्टि बनी रहेगी। इस बीच कोई बाल बांका भी न कर सकेगा। बस क्या था। तुरंत काल्पनिक घोड़े दौड़ाये जाने लगे। चटपट सुझाव पेश किया गया कि इसी दौरान मध्यावधि चुनाव करवा कर मंगल कार्य सिद्ध किया जाये। शुभ कार्य में देरी क्यों ? अब यदि मार्च तक मध्यावधि चुनाव घोषित हो जायें, तो कोई आश्चर्य नहीं।

—रंजना कक्कड़

संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का कार्य प्रमुख रूप से सौंपा गया है। यद्यपि दीक्षितजी ने 'माया' से बातचीत में इससे इनकार किया है। अटकलों का दौर फिर भी जारी है।

अटकलें इस खबर से भी बढ़ी हैं कि सत्तारूढ़ दल ने एक सर्वे करवाया है। इस सर्वे के अनुसार यदि चुनाव हुए, तो कांग्रेस-इ हारेगी तो नहीं, लेकिन उसको अल्पबहुमत मिलेगा। इस सर्वे को जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर गलत और प्रचार का हथकंडा मानते हैं।

दूसरी अजीब अटकल यह है कि कांग्रेस-इ को अकेले सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन वह जीतनेवाली सबसे बड़ी अकेली पार्टी होगी और संभव है कि सरकार बनाने में भाजपा भी उसका सहयोग करे। इसका कारण सरसंघ चालक बालासाहब देवरस का वह बयान माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस-इ का कोई विकल्प नहीं। तीसरी अटकल यह है कि मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस-इ की पराजय होगी और सभी विपक्षी दलों की मिली-जुली सरकार बनेगी।

बहरहाल इस पूरे दौर में, जब तक स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती, तब तक देश भर का मतदाता भी दुविधा, संशय और अनिर्णय के बीच अटका रहेगा। इस बीच यदि किसी को लाभ होगा, तो केवल चुनाव के नाम पर अनापशनाप चंदा बटोरने वालों को।

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

चुनाव खर्च

अकसर यह बात भुला दी जाती है कि चुनाव कराने में आर्थिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रशासनिक और राजनीतिक। चुनाव चाहे पंचायत स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का, उसमें उसी उम्मीदवार को विजय मिल सकती है, जिसके पीछे धनसत्ता हो। चुनाव केवल धन शक्ति के आधार पर न लड़े जायें, इसलिए सरकार संसदीय चुनाव में हरेक उम्मीदवार को डेढ़ लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत देती है। विधानसभाओं के मामले में १० से ५० हजार रुपए तक (निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार) कोई उम्मीदवार खर्च कर सकता है।

बहरहाल, इन नियमों को प्राय: भंग किया जाता है। जानकार सूत्रों के अनुसार निर्धारित राशि से दस गुनी से अधिक राशि खर्च की जाती है। दरअसल, चुनाव में काले धन का जमकर उपयोग होता है, इसलिए जब-जब चुनाव होता है तब-तब राष्ट्रीय कोष भी प्रभावित होता है।

मुद्रास्फीति को देखते हुए मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि संसदीय चुनाव में एक उम्मीदवार को लगभग १५ लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। इस तरह यदि अभी मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो कुल कितना खर्च आयेगा ? यदि हरेक निर्वाचन क्षेत्र में तीन कड़े प्रतिद्वंद्वी हों, तो खर्च आयेगा लगभग ४५ लाख रुपए। यदि हम इसे लोकसभा को कुल ५४५ सीटों से गुणा कर दें, तो २४५ करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आयेगा। यह अनाप-शनाप खर्च मध्यावधि चुनाव होने पर लाजिमी है।

संसदीय चुनावों में एक उम्मीदवार औसतन कितना धन खर्च करता है और किन-किन मदों पर करता है, इसके लिए ८०० मतदान केंद्रों को आधार बनाकर 'माया' द्वारा मोटे तौर पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

मद	**खर्च**
परिवहन और ईंधन	
(क) ३० दिनों के लिए—हर १०० मतदान केंद्रों हेतु—एक गाड़ी कार्यकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए। एक संसदीय चुनाव क्षेत्र के लिए कुल गाड़ियों की संख्या—८, एक गाड़ी का किराया खर्च: ५०० रुपए रोजाना कुल लागत: ५००x८x३०---	१,२०,००० रुपए
(ख) ईंधन—८ कारों के लिए रोजाना औसत २०० लीटर पेट्रोल (७.५० रुपए प्रति लीटर)	४५,००० रुपए
(ग) मतदान के दिन गाड़ियों का इस्तेमाल—प्रति दो मतदान केंद्रों के लिए—एक जीप, एक टैम्पो, एक लारी या आटो कुल: ८००÷२ ४०० किराया लागत: ३०० रुपए प्रति गाड़ी मय ईंधन कुल: ४००x३००	१,२०,००० रुपए
कार्यकर्ताओं को भुगतान	
(क) एक व्यक्ति—२००० मतदाताओं के मतदान क्षेत्र में (दो मतदान केंद्र) १० दिनों के लिए पारिश्रमिक (५० रुपए रोजाना) ४०० कार्यकर्ताओं का कुल खर्च: ४००x१०x५०---	२००००० रुपए
(ख) मतदान के दिन-हरेक मतदान केंद्र के लिए दो मतदान एजेंटों की तैनाती पारिश्रमिक: १०० रुपए प्रति एजेंट कुल: ८००x२x१००	१,६०,००० रुपए
(ग) हरेक मतदान केंद्र पर परिचय पत्र जारी करने और मतदाताओं को लाने के लिए दो एजेंटों की तैनाती कुल: ८००x२x१००	१,६०,००० रुपए
(घ) मतों की गिनती के लिए—सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग १५० साथ में आठ अतिरिक्त एजेंट चुनाव अधिकारी की मेज के पास मौजूदगी के लिए। कुल एजेंटों की तादाद: १५८ पारिश्रमिक: १५८x५०	७,९०० रुपए
चुनाव सामग्रियां और प्रचार	
(क) परिचयपत्र हरेक मतदाता के लिए (छह लाख मतदाता) छपाई और लिखाई खर्च आदि: ३ पैसा प्रति पर्चा कुल: ०.०३x६०००००	१,८००० रुपए
(ख) ५०००० पोस्टर (चुनाव क्षेत्रों के लिए, ४ रुपए प्रति पोस्टर) कुल: ५००००x४	२००००० रुपए
(ग) पैम्फलेट, बैज, बैनर, लीफलेट्स आदि (१०० रुपए प्रति मतदान क्षेत्र) कुल: ८००x१००	८०००० रुपए
(घ) सार्वजनिक सभाएं, जुलूस आदि (तीन-तीन हरेक विधानसभा क्षेत्र के लिए, १०० मतदान केंद्र) रुपए २५०० प्रति सार्वजनिक सभा कुल: ८x३x२५००	६०००० रुपए
(ङ) कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक (लोगों को सभाओं में लाने आदि का) मोटा हिसाब	५४००० रुपए
(च) सभा को संबोधित करनेवाला एक राष्ट्रीय नेता	१२००० रुपए
फुटकर खर्चे	५००० रुपए
कुल खर्च रुपए	**१२,४१,००० रुपए**

, १९८९ की मौजूदा मुद्रास्फीति में यह खर्च लगभग १५ लाख रुपए होगा।

—प्रकाश नंदा

नौकरशाही

देशी अफसरों को विलायती प्रशिक्षण

गृह राज्यमंत्री पी॰ चिदंबरम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षकों को विदेश में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' का जो नया कार्यक्रम बनाया है, उसमें ऐसे कौन से खतरे विद्यमान हैं कि विपक्ष के साथ-साथ स्वयं सत्ता पक्ष के नेता इसका घोर विरोध कर रहे हैं?

भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए अमरीका तथा ब्रिटेन भेजने की गृहमंत्रालय की योजना का चारों ओर से विरोध शुरू हो गया है। ११ नवंबर को लोकसभा में उस समय अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित हो गया, जब कम्युनिस्ट सांसद विजय कुमार यादव ने उक्त योजना का मामला सदन में उठाया। गृहराज्य मंत्री पी॰ चिदंबरम इस योजना का बचाव कर रहे थे, तभी कांग्रेस-इ के महामंत्री और वरिष्ठ सांसद भगवत झा आजाद ने हस्तक्षेप करते हुए भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाने का कड़ा विरोध किया। श्री आजाद का विपक्ष के सदस्यों ने भी समर्थन किया और चिदंबरम का स्पष्टीकरण सांसदों के शोर-शराबे में डूब गया। श्री आजाद की मान्यता है कि हमारे अपने प्रशिक्षण संस्थान विदेशी संस्थानों से बेहतर हैं, लेकिन इस योजना का विरोध प्रमुख रूप से दो आशंकाओं के कारण हो रहा है। पहली आशंका यह है कि विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान भारतीय अधिकारियों के बीच विदेशी गुप्तचर एजेंसियां घुसपैठ कर सकती हैं, दूसरी आशंका यह है कि ये अधिकारी विदेश में जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वह भारतीय संदर्भों के उपयुक्त होगा भी या नहीं।

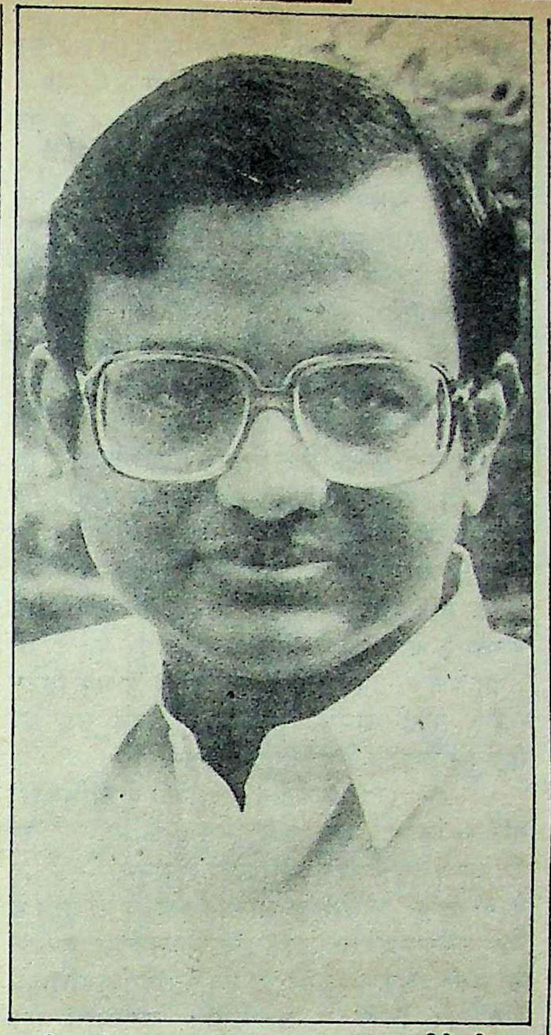

कार्यक्रम के सूत्रधार: पी॰ चिदंबरम

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

कार्यक्रम: योजना यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित प्रशिक्षक उच्च प्रशिक्षण के लिए अमरीकी, फ्रैंच और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में और पुलिस सेवा के प्रशिक्षक वर्जीनिया और स्काटलैंड यार्ड भेजे जायेंगे। ऐसे अनेक मामले पहले हो चुके हैं, जिनमें प्रशिक्षण के लिए विदेश गये भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की चूक से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां विदेशी गुप्तचरों के हाथों में पड़ गयीं। जब यशवंतराव बलवंतराव चह्वाण सुरक्षा मंत्री थे तब उनके मंत्रालय के एक आई॰ए॰एस॰ अधिकारी को उच्च प्रशिक्षण के लिए हारवर्ड विश्वविद्यालय भेजा गया था। वहां के एक प्रोफेसर से बातचीत के दौरान उस अधिकारी के मुंह से ऐसे ही निकल गया कि भारत परमाणु बम बनाने में सक्षम है। उक्त प्रोफेसर ने यह वार्तालाप शब्दश: अमरीका के विदेश विभाग को बता दिया। इस बातचीत के कुछ दिनों बाद भारत ने पोखरन में सफल परीक्षण किया। इससे अमरीका के विदेश विभाग को उक्त अधिकारी की बातों की पुष्टि हो गयी। अमरीका स्थित भारतीय दूतावास को जब अमरीकी सरकार के हाथ लगे उक्त वार्तालाप का पता चला, तो उसने उक्त अधिकारी के खिलाफ नयी दिल्ली को एक रिपोर्ट भेजी। तत्काल उस अधिकारी की तरक्की रोक दी गयी, लेकिन रक्षामंत्री चह्वाण ने हस्तक्षेप किया और अंततः उक्त अधिकारी भारत सरकार के सचिव-पद से सेवानिवृत्त हुए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, "उक्त घटना उन खतरों की ओर संकेत करती है जो ऐसे अधिकारियों को विदेश भेजे जाने में निहित हैं, जिन्हें बाद में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है।" बताया जाता है कि इन सब आशंकाओं के बावजूद सरकार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का मन बना चुकी है। बताया जाता है कि यह कार्यक्रम कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन संबंधी मामलों के राज्यमंत्री पी॰ चिदंबरम के दिमाग की उपज है, लेकिन कार्मिक मंत्रालय के प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, 'इसे प्रधानमंत्री का वरदहस्त भी प्राप्त है।'

वस्तुतः 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम की अवधारणा की जड़े राजीव गांधी की इस घोषणा में निहित हैं कि प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि यह तंत्र ह्रासोन्मुख हो गया है। राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद यह अनुभव किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करनेवाले विशेषज्ञ शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और जो हैं उन्हें और योग्य बनाने की आवश्यकता है। इसी कारण विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम का जन्म हुआ।

विरोध के मुद्दे: अभी तक का अनुभव तो यह रहा है कि विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटने के बाद बहुत कम प्रशासनिक अधिकारी भारतीय संस्थानों में अपने साथियों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार होते हैं। अतः इस नये कार्यक्रम में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटने के बाद हर अधिकारी को भारतीय संस्थानों में कम-से-कम तीन वर्ष तक पढ़ाना होगा। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इनके मूल वेतन में तीस प्रतिशत वृद्धि कर दी जायेगी। इस प्रोत्साहन के बावजूद इस नये कार्यक्रम का बुद्धिजीवी और स्वयं प्रशासनिक अधिकारी घोर विरोध कर रहे हैं। एक उच्च पदस्थ आई॰ए॰एस॰ अधिकारी इस कार्यक्रम को अनुपयुक्त बताते हैं, तो भूतपूर्व आई॰पी॰एस॰ अधिकारी और बड़ौदा शहर के मेयर जसपाल सिंह इसे नयी सत्ता की एक और कपोलकल्पना बताते हुए इसकी आलोचना करते हैं। हारवर्ड विश्वविद्यालय के भूतपूर्व परामर्शदाता रह चुके मोहन गुरुस्वामी के अनुसार, "हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डेरेक बोक ने इस नये कार्यक्रम पर मेरे विचार जानने के लिए मुझसे संपर्क किया था।" जब मैंने बताया कि यह बेकार का कार्यक्रम लगता है, तो उनका जवाब था, "मैं भी ऐसा ही मानता हूं, लेकिन चिदंबरम ने इस पर बड़ा जोर दिया था।"

फोर्ड फाउंडेशन का विरोध: 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में अमरीका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान की सलाहकार की भूमिका है। यद्यपि इस फाउंडेशन ने भारत की हरित-क्रांति योजना में अच्छा योगदान दिया था, लेकिन इस कार्यक्रम से इस फाउंडेशन का जुड़ना भी विवाद

और आलोचना का विषय बन गया है। बहुतों का आरोप है कि अमरीका स्थित अधिकांश संस्थान खुफिया एजेंसियों को प्रश्रय प्रदान करते हैं। एक असंतुष्ट कांग्रेसी मुफ्ती मोहम्मद सईद के अनुसार, "पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोर्ड फाउंडेशन की भारत से शैक्षणिक संबंध स्थापित करने की कोशिशों का विरोध किया था।" यहां तक कि पचास के दशक में न्यूयार्क टाइम्स ने यह संकेत दिया था कि सी०आई०ए० की गतिविधियों का फोर्ड फाउंडेशन भी एक केंद्र है। यह भी माना जाता है कि हारवर्ड स्कूल में भी सी०आई०ए० की घुसपैठ है। एक आई०ए०एस० अधिकारी का कहना है, "व्यावहारिक रूप से अमरीका के सारे संस्थान सी०आई०ए० से कोई-न-कोई संबंध अवश्य रखते हैं और फोर्ड फाउंडेशन को इसका अपवाद नहीं कहा जा सकता।"

बहरहाल, उक्त तर्क के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत या किसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेश यात्रा पर जाता है, तो गुप्तचर एजेंसियों का शिकार हो सकता है। लोकदल-अ के महासचिव सुब्रह्मण्यम का सवाल है, "क्या आप समझते हैं कि सी०आई०ए० और के०जी०बी० राष्ट्रसंघ में गये प्रतिनिधिमडंल के सदस्यों पर नजर नहीं रखती हैं?" कुछ वरिष्ठ आई०पी०एस० अधिकारी तो शपथपूर्वक कहते हैं कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है, उससे पाश्चात्य विचारधारा का ही प्रचार होगा।

विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटे केंद्रीय सेवा के एक अधिकारी का कहना है, "इससे वास्तव में साम्राज्यवादी सभ्यता का ही विस्तार होगा। विदेशी ताकतें ऐसे कार्यक्रमों के जरिये तीसरी दुनिया के देशों के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए आमादा हैं।" लेकिन केंद्रीय सेवा के एक अन्य अधिकारी का मत है, "यह कहना हमारी समझ का अपमान है कि हम अपने हितों और विदेशियों के निहित स्वार्थों में अंतर करने में समर्थ नहीं हैं।" लेकिन वैचारिक 'ब्रेनवाश' का भय चीन को नहीं है। चीन अपने छात्रों को अमरीकी विश्वविद्यालयों में भेज रहा है। और-तो-और हमारा अपना शैक्षणिक ढांचा भी पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित है फिर भी इसने अनेक कट्टर समाजवादियों का निर्माण किया। मोहन गुरुस्वामी भी इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री सचिवालय के सलाहकार गोपी कृष्ण अरोड़ा सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी वामपंथी विचारधारा के हैं, यद्यपि उन्होंने हारवर्ड सहित अमरीका और ब्रिटेन के शिक्षण-संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की थी। श्री गुरुस्वामी का कहना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के विरोध में दिये गये इन तर्कों में दम नहीं है। केंद्रीय सेवा के एक अन्य अधिकारी तो गुस्से से कहते हैं, "जिस क्षण अमरीका का नाम आता है, वामपंथी लाबी सी०आई०ए० का शोर मचाना शुरू कर देती है, लेकिन सोवियत रूस के नाम पर ऐसी हाय-तौबा क्यों नहीं मचती? ऐसा लगता है कि पश्चिम के संबंध में हम पूर्वग्रहों से ग्रस्त हो गये हैं।" इस बात से सुब्रह्मण्यम स्वामी तहेदिल से सहमत हैं। वह बताते हैं, "यहां तक कि बंगाली मार्क्सवादी अमरीका में पढ़ा रहे हैं और 'समाजवाद' के मुखौटे में वे सब 'पूंजीवाद' के लाभों का उपयोग कर रहे हैं।"

एक खतरा यह भी: 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में यह खतरा भी विद्यमान है कि हमारे अधिकारियों में प्रशिक्षण देनेवाले देश के प्रति विशेष सहानुभूति पैदा हो सकती है। फिलहाल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विदेश में जिन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनमें यह संभावना रहती है कि प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाला उस देश की विचारधारा से प्रभावित हो सके। यही वजह है कि अधिकांश देश इन प्रशिक्षणार्थियों के साथ बहुत ही सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। ब्रिटेन के बारे में तो कहा ही जाता है कि उसने तो सिद्धांत ही बना लिया है कि यदि कोई विदेशी ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके अनुभव बड़े मधुर रहे हैं, तो अपने देश लौटने पर जब भी उसके सामने ब्रिटेन संबंधी कोई मामला आयेगा, तो वह उस पर सहानुभूतिपूर्वक अनुकूल रुख अपनायेगा।

इस संदर्भ में केंद्रीय सेवा के एक अधिकारी तमिलनाडु की एक फर्म 'मेत्तुर केमिकल्स' का उदाहरण देते हैं। इस अधिकारी के अनुसार इस फर्म ने भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च गुणवत्ता के पोलिसिलिकन चिप्स सप्लाई करने की पेशकश की थी, लेकिन संबंधित मंत्रालय के अमरीकी हितों से सहानुभूति रखनेवाले एक उच्चाधिकारी ने इस फर्म का विरोध किया और भारत सरकार को सलाह दी कि वह इन पोलिसिलिकन चिप्सों के लिए अमरीका की हेमलाक कार्पोरेशन की पेशकश को स्वीकार कर ले, जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि अमरीकी फर्म की तकनीक पुरानी पड़ चुकी थी और उसकी कीमत भी मेत्तुर केमिकल्स द्वारा प्रस्तावित कीमत से चार गुना अधिक थी। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। बहरहाल, बताया जाता है कि अभी भी उक्त अधिकारी मेत्तुर केमिकल्स के खिलाफ जोड़-तोड़ में लगा है।

निरुपयोगी प्रशिक्षण: इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की योजना का तो खासतौर से विरोध हो रहा है। इसके लिए जिन अधिकारियों का चयन किया जायेगा, उनमें से अधिकांश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) से संबंधित होंगे। नयी दिल्ली के भूतपूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गौतम कौल के अनुसार इन अधिकारियों को खुफिया सूचनाएं एकत्र करने में महारत हासिल करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है। बहरहाल, ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटे केंद्रीय सेवा के एक अधिकारी तो इस कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रश्न-चिह्न लगाते हुए कहते हैं, "हो सकता है, यह प्रशिक्षण खुफिया सूचनाएं एकत्र करने की तकनीक विकसित करने में सहायक हो, लेकिन विदेशी सरकारें प्रायः ऐसी सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोगी नहीं होतीं।" एक अन्य गुप्तचर अधिकारी इस तथ्य का समर्थन करते हुए अमरीका और ब्रिटेन के दो लियाजां अधिकारियों का हवाला देते हैं। कुछ समय पहले ये दोनों अधिकारी नशीले पदार्थों की तस्करी को समाप्त करने में मदद देने के लिए भारत में तैनात किये गये थे, लेकिन इस संबंध में उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और किसी भी तरह मददगार साबित नहीं हुए। इसी प्रकार पाकिस्तान में १८ लियाजां अधिकारी तैनात किये गये, लेकिन इससे

सुब्रह्मण्यम स्वामी

दस वर्षों तक हारवर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके सुब्रह्मण्यम स्वामी भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, "इस कार्यक्रम का और कोई लाभ हो या न हो, यह अधिकारियों में मानसिक अनुशासन जरूर पैदा करती है। जो लोग अमरीकी संस्थानों में अध्ययन करने जाते हैं, उन्हें अपने कपड़े और अपने कमरे खुद ही साफ करने होते हैं, इससे उनका सामंती दृष्टिकोण टूट जाता है और उन्हें 'श्रम' की महत्ता का ज्ञान होता है।"

भी नशीले पदार्थों की तस्करी पर कोई अंकुश नहीं लग सका।

मध्यममार्गी: इस कार्यक्रम: का पुरजोर समर्थन व विरोध करनेवालों के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी है जो मध्यममार्गी हैं। इनकी मान्यता है कि जिन विषयों में प्रशिक्षण देने की सुविधा भारत में नहीं है, केवल उन्हीं विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को विदेश भेजा जाना चाहिए। लेकिन प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश में अधिकारियों को शिक्षण-विज्ञान में प्रशिक्षित किये जाने की योजना है। निश्चित रूप से भारत में ही ऐसे प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। यहां तक कि 'प्रशासकों को प्रशिक्षण' देने के कार्यक्रम में सामान्य प्रबंध संबंधी जो विषय शामिल किये गये हैं, उनके शिक्षण की बहुत बेहतर व्यवस्था भारत के प्रबंध संबंधी शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध है। बहरहाल, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) के०ए० चंद्रशेखरन इन विचारों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, "हमारे पास विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की संख्या बहुत कम है और प्रशासकों को जिन विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी संख्या १३० है। यही कारण है कि हमें और अधिक संख्या में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की आवश्यकता है।" फिर भारत सरकार अपने वर्तमान संस्थानों के स्तर को ऊंचा क्यों नहीं उठाती? एक अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने पर करीब ढाई लाख रुपए का खर्च आता है। इतने खर्चे में तो भारत में दस अधिकारी प्रशिक्षित किये जा सकते हैं। यहां तक कि स्वयं चिदंबरम यह स्वीकार करते हैं कि अपने संस्थानों की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। यह बात भी स्वीकार की गयी कि प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता तभी है जब 'भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' को व्यावहारिक रूप देने में इससे मदद मिल सके, साथ ही प्रशिक्षित अधिकारी उपयुक्त स्थान पर नियुक्त किये जायें। प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे भी मामले हुए हैं, जब किसी अधिकारी को ऐसे पद पर नियुक्त किया गया, जिसका उक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण से कोई संबंध नहीं था। बताया जाता है कि चिदंबरम ने इस विसंगति पर गौर किया है। फिर भी अधिकारियों को भय है कि न केवल नियुक्ति में, बल्कि प्रशिक्षण के लिए चयन करने के मामले में भी आई०ए०एस० अधिकारियों के पक्ष में मनमाना रवैया अपनाया जा सकता है। और यह भय निराधार नहीं है।

मुफ्ती मोहम्मद सईद

बहुतों का आरोप है कि अमरीका स्थित अधिकांश संस्थान खुफिया एजेंसियों को प्रश्रय प्रदान करते हैं। एक असंतुष्ट कांग्रेसी मुफ्ती मोहम्मद सईद के अनुसार, "पंडित जवाहर लाल नेहरू ने फोर्ड फाउंडेशन की भारत से संबंध स्थापित करने की कोशिशों का विरोध किया था।" यहां तक कि पचास के दशक में न्यूयार्क टाइम ने यह संकेत दिया था कि सी०आई०ए० की गतिविधियों का फोर्ड फाउंडेशन भी एक केंद्र है।

इस समय हालत यह है कि केंद्र में नियुक्त ६८ सचिवों में से ५६ सचिव आई०ए०एस० वर्ग के हैं। यद्यपि कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा, लेकिन अनेक गैर आई०ए०एस० अधिकारियों की मान्यता है कि 'विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम' के लिए अधिकारियों के चयन में उनका नंबर नहीं आयेगा। बहरहाल, कुछ अधिकारी इस कार्यक्रम के संबंध में बहुत उत्साहित हैं। उनका तर्क है कि भारतीय प्रशिक्षण, विदेशी प्रशिक्षण का विकल्प नहीं हो सकता। जैसाकि केंद्र सरकार के एक उपक्रम के अध्यक्ष कहते हैं, "विदेशी प्रशिक्षण ने मेरे कार्यक्षेत्र से संबंधित नियमों और कार्यप्रक्रिया के संबंध में मुझे अच्छी जानकारियां दी हैं, जिसके कारण मैं तकनीकी विषयों पर भी बातचीत करने के काबिल हो गया हूं। अब मैं भारत सरकार की सहभागिता में कार्य करने की पेशकश लेकर आये किसी भी विदेशी से और अधिक विश्वास के साथ बातचीत कर सकता हूं।"

जसपाल सिंह

प्रोत्साहन के बावजूद इस नये कार्यक्रम का बुद्धिजीवी और स्वयं प्रशासनिक अधिकारी घोर विरोध कर रहे हैं। एक उच्च पदस्थ आई०ए०एस० अधिकारी इस कार्यक्रम को अनुपयुक्त बताते हैं, तो भूतपूर्व आई०पी०एस० अधिकारी और बड़ौदा शहर के मेयर जसपाल सिंह इसे नयी सत्ता की एक और कपोलकल्पना बताते हुए इसकी आलोचना करते हैं।

प्रशिक्षण या पर्यटन: 'विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम' में अपना चयन करवाने के लिए अधिकारियों में जैसी होड़ मची है, उससे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता के ये अधिकारी कायल हो गये हैं, लेकिन इस होड़ का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों की दृष्टि में 'विदेश में प्रशिक्षण' का मतलब मौजमस्ती से भरा विदेश-भ्रमण होता है। गुरुस्वामी का कहना है कि कुछ अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश अधिकारी इसे अतिरिक्त बोनस मानते हैं। वे कक्षा से गायब रहते हैं, या विलंब से आते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। अन्य देशों के विपरीत ये अधिकारी अपने साथ अपना परिवार भी ले जाते हैं। एक अधिकारी तो अपने साथ अपनी दादी को भी ले गया था।

साक्षात्कार/पी॰चिदंबरम

राज्यमंत्री, भारत सरकार

पहले चलना तो सीखें

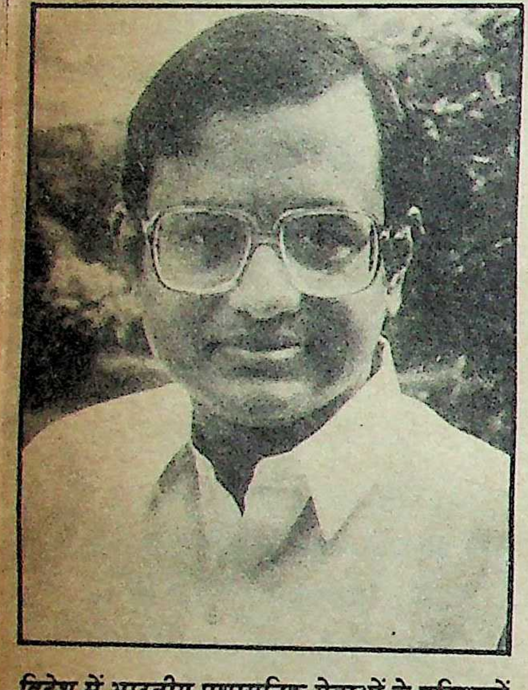

विदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना कार्यान्वित होने से पहले ही आलोचना का विषय बन गयी है। कहा जाता है कि यह योजना कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन संबंधी मामलों के राज्यमंत्री पी॰ चिदंबरम के दिमाग की उपज है। 'माया' ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जब पी॰ चिदंबरम से मुलाकात की, तो उनका यही कहना था, "जब भी कोई राजनेता कोई विचार प्रस्तुत करता है, तो २० अन्य राजनेता उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं।" चिदंबरम बड़ी मुश्किल से भेंटवार्ता देने के लिए तैयार हुए। उनका कहना था, "मैं चुप रहना बेहतर समझता हूं, क्योंकि चुप रहना ही सर्वोत्तम नीति है।" यद्यपि उन्होंने सवालों के उत्तर बड़ी शालीनता से दिये, लेकिन बातचीत के दौरान वह उद्विग्न भी हो जाते थे—खासकर आरोपों के संबंध में जिनके बारे में उनका कहना था कि ये तथ्यहीन हैं। भेंटवार्ता की समाप्ति पर बड़ी अधीरता से उन्होंने कहा, "मुझे परवाह नहीं है कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता से आप सहमत हैं या नहीं। यदि आप सहमत हैं, तो ठीक, यदि नहीं तो मुझे इसकी परवाह नहीं।" विश्वास करना चाहिए कि यह बात उन्होंने दंभपूर्वक नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास के कारण कही है। यहां प्रस्तुत हैं, पी॰ चिदंबरम से सुधा भाटिया की ४० मिनट तक हुई बातचीत के प्रमुख अंश :

माया: 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम पर कुल कितना खर्चा आयेगा?

चिदंबरम : इस क्षण तक हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसके लिए कोई कोष निर्धारित नहीं है, सारी बातें अभी खोजबीन के स्तर पर हैं।

माया: भारत में प्रशिक्षित आई॰ए॰एस॰ अधिकारी उतने ही अच्छे या बुरे माने जाते हैं, जितने कि ब्रिटेन में प्रशिक्षित आई॰सी॰एस॰ अधिकारी माने जाते थे। फिर क्या यह जरूरी है कि हम अपने अधिकारियों को विदेश भेजकर यह जोखिम उठायें कि विदेशी गुप्तचर इनमें घुसपैठ के प्रयास कर सकें। आखिरकार हमारे जैसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में ऐसी घुसपैठ के खतरे विद्यमान रहते हैं।

चिदंबरम : 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण', 'प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण' से भिन्न है। पिछले दो दशकों से औसतन १३० लोग 'प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष विदेश भेजे जा रहे हैं। इनमें कुछ ही लोग भारतीय प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित रहते हैं। प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लेने के बाद हम 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम का जायता ले रहे हैं। हम अपने इस प्रशिक्षण विभाग में सुधार करना चाहते हैं। संक्षेप में हमारा विश्वास है कि इस विभाग में तभी सुधार हो सकता है जब हम इस विभाग के कुछ लोगों को शिक्षण पद्धति, प्रकरण लेखन और पाठ्यक्रम निर्धारण विज्ञान के संबंध में नयी जानकारियां प्राप्त करने के लिए बाहर भेजें। मेरा यह कहना नहीं है कि ये सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं है, बल्कि स्थिति यह है कि ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः यदि इस विभाग के कुछ लोग बेहतर संस्थानों में जा सकते हैं और वहां से नया कौशल सीखकर अपने प्रशिक्षण संस्थानों में वापस आते हैं, तो इससे यह विभाग समृद्ध होगा।

माया: आप प्रशासनिक सेवाओं से बाहर के लोगों को प्रशिक्षक के रूप में तैयार नहीं करते?

चिदंबरम : इन प्रशिक्षकों में अनेक लोग वास्तव में प्रशासनिक सेवाओं से बाहर के हैं। वे रीडर, प्रोफेसर और लेक्चरर हैं।

माया: ऐसा अनुभव किया जाता है कि हमारे प्रशासनिक महाविद्यालयों के स्टाफ में सर्वोच्च प्रतिभाएं नहीं हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? जैसाकि आप प्रशासनिक सेवाओं के 'प्रशिक्षकों' के लिए करने जा रहे हैं?

चिदंबरम : इस विभाग में दो प्रकार के प्रशिक्षक हैं—एक स्थायी दूसरे स्थानापन्न। प्रशासकीय महाविद्यालयों के 'प्रशासकीय शिक्षक' इस विभाग के स्थानापन्न सदस्य होतें हैं। अब यदि भारत सरकार प्रशासनिक सेवाओं के लोगों को इस विभाग में नियुक्त करती है, तो उन्हें प्रोत्साहन भी देती है जिससे वे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा सकें। लेकिन जहां तक इस विभाग के स्थायी प्रशिक्षकों का सवाल है, उन्हें बहुत ही आकर्षक वेतनमान देना होगा—लेकिन यह राज्य सरकारों का काम है जो ऐसे 'प्रशिक्षण' संचालित करती है। मैं तो यही कह सकता हूं कि इनके वेतनमान और भत्ते इतने अच्छे होने चाहिए कि राज्य सरकारों को अच्छे और स्थायी प्रशिक्षक प्राप्त हो सकें।

माया : इस कार्यक्रम में 'फोर्ड फांउडेशन' की भूमिका को लेकर खासकर इस संगठन के पिछले कारनामों को देखते हुए अनेक संदेह पैदा हो गये हैं। पचास के दशक में न्यूयार्क टाइम्स ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि यह सी॰आई॰ए॰ गतिविधियों में सहयोगी अनेक अमरीकी संस्थानों में से एक है। आपकी प्रतिक्रिया?

चिदंबरम : यह सवाल तो भारत के विदेश मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग से पूछा जाना चाहिए जो फोर्ड फाउंडेशन के कोष का काम देखते हैं।

माया : लेकिन इस कार्यक्रम के सभी पक्षों के संबंध में जवाबदेह तो आप ही हैं?

चिदंबरम : यदि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, तो मैं यह देखना चाहूंगा कि यह धनराशि प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षण जरूरतों के सर्वोत्तम हित में कैसे खर्च की जा सकती है? इस सवाल का जवाब देना मेरा काम नहीं है कि कोई एजेंसी या संगठन इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए या नहीं?

माया: लेकिन गृह राज्यमंत्री होने के कारण निश्चित रूप से आप इस स्थिति में हैं...

चिदंबरम : (हस्तक्षेप करते हुए) वैसे अभी तक ऐसे संस्थानों के बारे में पता लगाने के लिए दो टीमें विदेश का दौरा कर चुकी हैं।

माया : सरकार प्रायः सभी मामलों में अस्थिरता के लिए सी॰आई॰ए॰ को जिम्मेदार ठहरा देती है। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि विदेश में 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' से सरकार विपक्ष को हमला करने के लिए उकसा रही है?

चिदंबरम : मैं समझता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं के विरुद्ध यह सर्वाधिक लचर आरोप है। यह मान लेना प्रशासनिक सेवा का सबसे बड़ा अपमान है कि यदि इसके कुछ सदस्य इस विभाग की तरक्की के लिए किसी कार्यक्रम के अंतगर्त विदेश जायेंगे, तो वे सी॰आई॰ए॰ एजेंट बन जायेंगे।

माया : ऐसा आरोप है कि आप हारवर्ड संस्थान को इस कार्यक्रम से जोड़कर सरकारी नीति पर अपने व्यक्तिगत विचारों को थोपना चाहते हैं?

चिदंबरम : ऐसे विचाराधीन संस्थाओं की संख्या २५ है, हारवर्ड उनमें से एक है।

माया : लेकिन इनमें अधिकांश संस्थाएं अमरीकी हैं।

चिदंबरम : इनमें से अनेक संस्थान इंग्लैंड में हैं, कुछ अमरीका और फ्रांस में। हमारी बाध्यता यह है कि हम केवल उन्हीं देशों में जा सकते हैं जहां अंग्रेजी में शिक्षण होता है। अतः कुछ खास देशों में ही जाना हमारे लिए जरूरी हो गया है।

माया : मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आरोप लगाया है कि

आप भारत में अमरीका जैसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं।

चिदंबरम: मुफ्ती मोहम्मद सईद अचानक असंतुष्टों के बुद्धिजीवी मार्गदर्शक बन बैठे हैं। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं की प्रशिक्षण जरूरतों का कोई ज्ञान नहीं है।

माया: आई०पी०एस० अधिकारियों को एफ०बी०आई० (फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) और स्काटलैंड यार्ड जैसी संस्थाओं में भेजा जा रहा है। क्या इस योजना से गुप्तचर एजेंसियों को इन अफसरों में घुसपैठ करने का मौका नहीं मिलेगा?

चिदंबरम: आप भूल रहे हैं कि हमारी योजना 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' देने की है, न कि 'प्रशासकों को प्रशिक्षण' देने की।

माया: सवाल पाठ्यक्रम के विषयों का नहीं है, घुसपैठ का खतरा तो इस योजना में भी उतना ही है।

चिदंबरम: राजनेता समझते हैं कि उनके अलावा राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। जब भी कोई राजनेता कोई विचार प्रस्तुत करता है, तो बीसियों अन्य राजनेता उस पर हमला शुरू कर देते हैं। रामधन और मुफ्ती मोहम्मद सईद इस मामले में क्या जानते हैं?

चलना सीखने से पहले दौड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले चलना तो सीखें। प्रशिक्षण अपने आप में उपेक्षित क्षेत्र रहा है। पिछले ढाई वर्षों से जब से यह सरकार बनी है, हम प्रशिक्षण पर सर्वाधिक जोर दे रहे हैं।

माया: 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम के पीछे नया विचार क्या है?

चिदंबरम: यह नया नहीं है। विभाग के सदस्यों को आज भी डेपुटेशन पर प्रशिक्षण हेतु थोड़े या ज्यादा समय के लिए विदेश भेजा जाता है। हां, पहली बार हम इसे बिलकुल खुले रूप से लागू कर रहे हैं और इसीलिए यह नयी नीति लग रहा है। जिन्हें गत २० वर्षों से इस सरकारी नीति की जानकारी नहीं है, वे ही इसकी अनर्गल आलोचना कर रहे हैं।

माया: 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम क्या लंबे समय तक चलेगा? क्या हम अपने यहां इस प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित नहीं कर सकते?

चिदंबरम: अभी तो यह कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन यह कार्यक्रम यदा-कदा ही होगा। संक्षेप में, जब तक हम अपने यहां शिक्षण, प्रकरण-लेखन और पाठ्यक्रम निर्धारण आदि में अच्छी कुशलता अर्जित नहीं कर लेते तब तक हमें विख्यात संस्थानों पर ही निर्भर रहना होगा।

माया: इस कौशल को विकसित करने की हमारे पास क्या कोई व्यवस्था है?

चिदंबरम: फिलहाल तो हम अवसरों की तलाश कर रहे हैं। यदि अवसर उपलब्ध हुए तो हमें एक विस्तृत योजना बनानी होगी और इसके लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। यदि धन की व्यवस्था नहीं हुई, तो हम किसी को नहीं भेजेंगे।

माया: हमारे जैसे देश की व्यवस्था के लिए अमरीकी व्यवस्था कैसे उपयुक्त रहेगी?

चिदंबरम: हम लोगों को शिक्षण-कौशल और प्रकरण-लेखन में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विदेश भेजेंगे। यहां वापस आकर वे इस देश की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करेंगे। इसे किसी सिद्धांत से कुछ लेना-देना नहीं है।

माया: हमें ऐसा कौशल अपने यहां विकसित करने और इस मामले में आत्मनिर्भर होने में कितना समय लगेगा?

चिदंबरम: अभी हमारे पास हर प्रदेश में एक प्रशिक्षण संस्थान है। हमें हर प्रांत में दो या तीन संस्थान स्थापित करने होंगे। इसमें दो या तीन वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन यह विकास लगातार जारी रहेगा।

माया: क्या हम अपने यहां ऐसा प्रशिक्षण कौशल विकसित नहीं कर सकते जिससे हम न केवल अविकसित, बल्कि विकसित देशों को भी प्रशिक्षण के लिए अपने यहां बुला सकें।

चिदंबरम: चलना सीखने से पहले दौड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले चलना तो सीखें। प्रशिक्षण अपने आप में उपेक्षित क्षेत्र रहा है। पिछले ढाई वर्षों से जब से यह सरकार बनी है, हम प्रशिक्षण पर सर्वाधिक जोर दे रहे हैं। हमारे जो संस्थान सुप्त हो रहे थे अब उनमें जीवंतता आ गयी है। वास्तव में अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था को विकसित करें न कि इसमें सहायक होनेवाले कार्यक्रमों पर पानी फेर दें।

अधिकांश देशों की सरकारें प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विदेश भेजे गये अधिकारियों को अपना परिवार साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती, जबकि भारतीय अधिकारियों को इसकी इजाजत मिली हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि विदेश में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की अवधि बनकर रह जाती हैं। एक अधिकारी इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, "अनेक कार्यक्रमों के तहत विदेश के जो शैक्षणिक दौरे आयोजित किये जाते हैं वे शैक्षणिक कम सैरसपाटे के लिए अधिक होते हैं, और अमरीका के उन्मुक्त समाज में मैं बहक न जाऊं इसलिए अपना परिवार अपने साथ ले जाता हूं।" इसके साथ ही इस अधिकारी का यह भी कहना है कि अधिकांश आई०ए०एस० अधिकारियों को अपने बड़प्पन का अहं होता है और विदेश के ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इस अहं को तोड़ देते हैं। एक अन्य आई०ए०एस० अधिकारी इस बात से सहमति प्रगट करते हुए कहते हैं, "वहां कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि भारत में हमारी हैसियत क्या है?" दस वर्षों तक हारवर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके सुब्रह्मण्यम स्वामी भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, "इस कार्यक्रम का और कोई लाभ हो या न हो, यह अधिकारियों में मानसिक अनुशासन जरूर पैदा करती है। जो लोग अमरीकी संस्थानों में अध्ययन करने जाते हैं, उन्हें अपने कपड़े और अपने कमरे खुद ही साफ करने होते हैं, इससे उनका सामंती दृष्टिकोण टूट जाता है, और उन्हें 'श्रम' की महत्ता का ज्ञान होता है।" इसके बावजूद इस बात का भी खतरा रहता है कि कुछ अधिकारी विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद और भी 'बड़ा साहब' या 'पक्का साहब' बन सकते हैं और अपने मातहतों के साथ बड़ी बेरुखी से पेश आ सकते हैं। विदेशी घुसपैठ के खतरे से यह खतरा कहीं अधिक बड़ा है। विदेशी खुफिया घुसपैठ के खतरे को कम आंकते हुए मोहन गुरुस्वामी का कहना है कि यदि वास्तव में यह खतरा है, तो ट्रिनिटी कालेज केंब्रिज में अध्ययन करने के कारण तो राजीव गांधी को भी ब्रिटिश एजेंट बन जाना चाहिए था।

असलियत यह है कि विदेश में प्रशिक्षण के लिए गया कोई भी अधिकारी किसी विदेशी सरकार के लिए गुप्तचरी करता हुआ नहीं पकड़ा गया। न ही ऐसी बात है कि जितने अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत विदेश भेजे जाते हैं वे सभी अपने देश से विश्वासघात ही करते हों। लेकिन यह खतरा न होने पर भी इस सवाल की महत्ता कम नहीं होती कि हमें 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' देनेवाले भारतीय संस्थानों की क्षमता का विकास क्यों नहीं करना चाहिए जिससे ऐसे प्रशिक्षण के मामले में विदेशों पर हमारी निर्भरता समाप्त हो सके। एक जाने-माने अवकाशप्राप्त गृह सचिव का कहना है, "हारवर्ड विश्वविद्यालय जाने के बजाये हमें अपने देश में ही ऐसा संस्थान स्थापित करना चाहिए और चिदंबरम का भी यही चरम लक्ष्य होना चाहिए।"

—सुधा भाटिया

युवाइंका

अभी तो आपस में लड़ रहे हैं

मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस-इ पर काबिज होने के लिए प्रदेश इंका के विभिन्न गुटों ने इतना उत्पात मचाया कि अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ठाकुर को छोड़कर आलाकमान ने समूची कार्यकारिणी को भंग कर दिया, लेकिन जब से सांसद सुरेश पचौरी ने आयु सीमा पार कर जाने के कारण युवा इंका के अखिल भारतीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है और श्री ठाकुर के उनके स्थान पर महासचिव बनने की अटकलें सरगर्म हुई हैं, तब से प्रदेश युवा इंका में जोड़-तोड़ का खेल और तेज हो गया है। जोड़-तोड़ में लगे, ये विभिन्न गुट किसके हैं और वे प्रदेश युवा इंका पर हावी होने के लिए जो उठापटक कर रहे हैं, उसका प्रदेश की इंका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ?

गुटबाजी में परोक्ष भूमिका : मोतीलाल वोरा

क्या वर्चस्व कायम रहेगा ?: सुरेश पचौरी

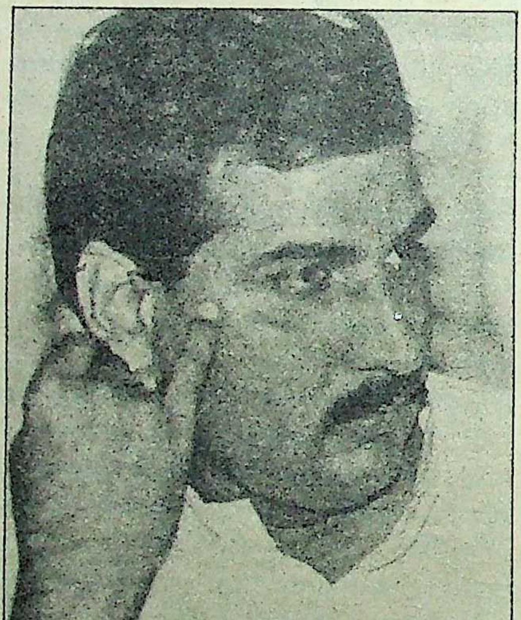

पचौरी की मेहरबानी : सुरेन्द्र सिंह ठाकुर

मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस—इ में इन दिनों बावेला मचा हुआ है और हालात ऐसे हैं कि इसे 'प्याली में तूफान' की संज्ञा देकर टाला या अनदेखा नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष, संगठन या सेवा दल की भांति यूथ कांग्रेस की राजनीति भी लाबियों में बंटी हुई है और लाबियों के टकराव और उठापटक का खेल प्रदेश के दिग्गज नेताओं की मेहरबानी से इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है कि यह संघर्ष द्वंद्वरत पक्षों के लिए अस्तित्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई का पर्याय हो गया है। संघर्षरत दो पक्षों में एक पक्ष वह है जो वर्तमान में प्रदेश युवा इंका पर काबिज है। दूसरा पक्ष वह है, जिसने वर्तमान नेतृत्व को हटाने के लिए कमर कस रखी है और इन दिनों आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर रखी है। इस पक्ष की आक्रामक मुद्रा को देखते हुए दूसरे पक्ष को बचाव पक्ष कहा जा सकता है जो यह बात भली भांति जानता है कि उसकी हल्की सी चूक उसे केंद्र से उठाकर परिधि में फेंक सकती है या मुख्य धारा से हटाकर बित्ते भर हाशिये में कैद कर सकती है।

अहमियत : प्रधानमंत्री से सीधे संबंधों और उनके प्रति असंदिग्ध निष्ठा के कारण सत्तारूढ़ दल के ढांचे में युवा इंका का एक अलग ही महत्व है। मध्यप्रदेश में युवक कांग्रेस का इतिहास प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री के प्रति अगाध और अटूट निष्ठा का पर्याय रहा है। चाहे १९६९ का कांग्रेस विभाजन रहा हो या १९७८ का, म०प्र० युवक कांग्रेस ने प्रादेशिक क्षत्रपों का मुंह जोहने के बजाय अपनी वफादारी श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति प्रकट की। सन ७८ में युवक कांग्रेस के नेता रामेश्वर नीखरा, बंशीलाल गांधी, गुफराने आजम आदि बगैर आगा-पीछा सोचे श्रीमती गांधी के पीछे आ खड़े हुए थे। यह परंपरा आज भी जारी है। इसके साथ ही यह भी सच है कि युवा इंका की प्रादेशिक इकाई अपनी रणनीति और स्थितियों व व्यक्तियों से सलूक का निर्धारण प्रादेशिक दिग्गजों व क्षत्रपों के बजाय केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त संकेतों, सूत्रों व नसीहतों के आधार पर करती है। यही वे संदर्भ हैं जो दिग्गज नेताओं को अपने प्रिय शिष्यों व जूनियर नेताओं को युवक कांग्रेस में पद दिलाने को प्रेरित करते हैं। क्रमिक तौर पर देखें, तो मध्यप्रदेश में शिव कुमार सिंह, बंशीलाल गांधी, प्रतापभानु शर्मा, रामेश्वर नीखरा, डा० भंवर सिंह पोर्ते, उत्तमचंद खटिक और मनोहर बैरागी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे, लेकिन म०प्र० यूथ कांग्रेस को एक निश्चित शक्ल, ताकत और पहचान तब मिली, जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के काल में सुरेश पचौरी अध्यक्ष बने। एक साधारण कृषक परिवार से संबंद्ध और अभियांत्रिकी स्नातक सुरेश पचौरी ने अपनी कर्मठता व सूझबूझ से प्रदेश की निष्प्राण युवा इकाई में नये प्राण फूंके। यह उनकी उपलब्धियों का ही परिणाम था कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट देकर पुरस्कृत किया। और तो और जब नया अध्यक्ष चुनने का वक्त आया, तो महारथियों की राय को दरकिनार रखकर उनकी इच्छा से सुरेंद्र सिंह ठाकुर को युवा इंकाध्यक्ष बनाया गया। श्री ठाकुर बाद में राज्यसभा के लिए भी चुने गये। जहां तक श्री पचौरी व श्री ठाकुर के सांसद बनने का प्रश्न है, इसे अनहोनी इस नाते नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ठा० शिव कुमार सिंह (खंडवा), प्रतापभानु शर्मा (विदिशा), रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) यूथ कांग्रेस के गलियारे से होकर संसद में पहले ही पहुंच चुके थे।

पूर्व-समीकरण : उपलब्ध सूचनाएं व संदर्भ बताते हैं कि अर्जुनसिंह व सुरेश पचौरी में अर्से तक गाढ़ी छनती रही और राजनीतिक दृष्टि से दोनों कभी-कभार साथ न भी चल पाये हों, तो भी दोनों में टकराव कभी नहीं हुआ। लेकिन सन ८५ और उसके बाद समीकरण धीरे-धीरे बदलने लगा और दोनों नेता भिन्न राहों के राही हो गये। लोगों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कला में माहिर मितभाषी दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने श्री पचौरी व उनके विश्वासपात्र श्री ठाकुर के बारे में जाहिरा तौर पर कभी कुछ नहीं कहा और सुरेश पचौरी उनके लिए कभी चुनौती नहीं बने। कुंवर साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में युवक कांग्रेस की बागडोर संभाल चुके पचौरी श्री सिंह की राजनीतिक ताकत और रुतबे, कूटनीतिक महारत और उनके 'लियाजां' से भली भांति परिचित थे। मगर इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो गयीं, जिन्होंने न केवल दोनों नेताओं को दूर-दूर कर दिया बल्कि आगे चलकर हालात ऐसे बन गये कि पचौरी-ठाकुर धुरी को अपनी अस्तित्व-रक्षा के लिए अर्जुन गुट की प्रश्रय प्राप्त युवा टुकड़ी से जूझना लाजिमी हो गया।

हिम्मत नहीं हारूंगी : सरला मिश्रा

१९८४ में लोकसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण का दौर चल रहा था। युवक कांग्रेस में तब महासचिव सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने राजगढ़ सीट से टिकट की याचना की। ठाकुर को राजगढ़ से टिकट तो नहीं मिला, लेकिन बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने इसे अपने क्षेत्र में अतिक्रमण माना। राजगढ़ से टिकट ठाकुर के बजाय अर्जुन सिंह के समधी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री दिग्विजय सिंह को मिला और वह चुने भी गये। कालांतर में मोतीलाल वोरा के मुख्यमंत्री बनने पर राजा साहब को प्रदेश इंकाध्यक्ष पद भी मिल गया। विधानसभा चुनाव का समय आया, तो बेरसिया से अर्जुन-दिग्विजय गुट के सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने टिकट मांगा। हालांकि सोलंकी अर्जुन-दिग्गी के कृपापात्र थे, मगर पचौरी की मार्फत दिल्ली दरबार की कृपा से सोलंकी का टिकट ठाकुर ले उड़े। राजनीतिक हलकों में इसे आश्चर्य से देखा गया। कहना न होगा कि यह उस धुरी के लिए गरल का घूंट था, जिसने टिकट वितरण के खेल में अच्छे-अच्छे राजनीतिक मल्लों को जमीन सुंघा दी थी। युवा इंका नेतृत्व के नजदीकी सूत्रों के अनुसार इसके बाद से पचौरी-ठाकुर अर्जुन-दिग्गी गुट की आंखों की किरकिरी बन गये और यह किरकिरी तब और तकलीफदेह हो गयी, जब पचौरी विधानसभा चुनाव में हारे हुए सुरेंद्र सिंह ठाकुर के लिए राज्यसभा का टिकट जुगाड़ लाये और ठाकुर पचौरी और किस्मत की मिलीजुली मेहरबानी से राज्यसभा के सदस्य हो गये। कटु संबंधों का करेला तब और नीम चढ़ गया, जब प्रदेश की राजनीति में पचौरी-ठाकुर और उनकी युवा नेताओं की टोली ने राजनीतिक द्वंद्व में मोतीलाल वोरा का दृढ़ता से साथ दिया। इस बीच श्री वोरा ने श्री सोलंकी को नागरिक सहकारी बैंक, भोपाल के अध्यक्ष पद से अपदस्थ किया, तो इसे सोलंकी और उनके राजनीतिक आकाओं ने सुरेंद्र सिंह ठाकुर की करतूत माना और उन्हें मन ही मन मजा चखाने का फैसला कर लिया। इसी दरम्यान, सांसद मार्तण्ड सिंह के पुत्र युवराज पुष्पराज सिंह को संभागीय मंत्री बनाये जाने से अर्जुन गुट की नाराजगी और अधिक बढ़ गयी। राजनीतिक शिविर में माना गया कि पचौरी विंध्य की राजनीति में नाहक दखलंदाजी कर रहे हैं और अजय सिंह उर्फ राहुल के कथित प्रतिद्वंद्वी को बढ़ावा दे रहे हैं।

नाटकीय मोड़ : इस घटनाक्रम के बाद अर्जुन गुट पचौरी-ठाकुर लाबी को मात देने की घात में लग गया, लेकिन अर्से तक उसे ऐसा कोई मौका हाथ नहीं लगा कि वह रणभेरी फूंकता और युवक कांग्रेस पर काबिज नेतृत्व पर प्रहार करता। ऐसे समय में अचानक कुमारी सरला मिश्रा का मंच पर प्रवेश हुआ और लकी कांड से शह और मात का ऐसा सिलसिला चला जिसने समूचे दृश्य में नाटकीय परिवर्तन कर डाला।

मध्यप्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन उपाध्यक्ष सरला मिश्रा सुर्खियों में यकबयक तब आयीं, जब वह बालक लकी शर्मा को साथ लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलीं। सरला ने प्रधानमंत्री से शिकायत की कि पचौरी-ठाकुर नेतृत्व ऐसे युवा वर्ग को संरक्षण दे रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान जबलपुर में चंसोरिया बंधुओं की अवांछित गतिविधियों की ओर भी आकृष्ट किया। तेजाब से बुरी तरह झुलसे हुए चेहरेवाले अबोध बालक लकी को देखकर प्रधानमंत्री का द्रवित होना स्वाभाविक था। उन्होंने अपनी विशेष सचिव सरला ग्रेवाल को तत्काल आदेश दिया कि बालक लकी के उपचार की व्यवस्था की जाये। उधर अध्यक्ष आनंद शर्मा तलब किये गये और संभागीय मंत्री आलोक चंसोरिया पद से हटा दिये गये। लकी कांड एक ऐसा मानवीय प्रसंग था, जिसकी गहरी त्रासदी सबको झकझोर गयी। इन्हीं दिनों सरला मिश्रा ने 'माया' से चर्चा में कहा "मैं जब लकी की मां की वेदना की कल्पना करती हूं जो रोज रात को लकी को आंचल से ढांपकर सुलाती होगी तो सिहर उठती हूं। मैं जानती थी कि मैं लोगों को नाराज कर रही हूं और ऐसा करते हुए मुझे जान का खतरा भी कम नहीं था, लेकिन मुझ पर यह जुनून हावी था कि मैं सचाई व न्याय के लिए लड़ रही हूं और इसी जुनून के वशीभूत मैं प्रधानमंत्री के पास चली गयी।"

कुमारी मिश्रा का यह आश्चर्य स्वाभाविक है कि किसी ने लकी कांड को उठाने और उजागर करने का साहस प्रदर्शित क्यों नहीं किया? जैसी कि आशंका थी उन्हें युवक कांग्रेस के आला नेतृत्व का कोपभाजन बनते देर नहीं लगी और जल्दी ही उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और कोई होता, तो ऐसे में हताश होकर बैठ जाता, लेकिन पदच्युत होने के बाद भी इस युवा नेत्री ने हिम्मत नहीं हारी। ९ अप्रैल को वह दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलीं। उनके साथ पंद्रह लड़कियों की टोली भी थी। उन्होंने ज्ञापन देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री से एक बार फिर शिकायत की कि मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस में ऐसा माहौल नहीं है कि लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए काम कर सकें। प्रधानमंत्री को दिये ज्ञापन में उन्होंने एक युवा इंका जिलाध्यक्ष का भी उल्लेख किया, जिस पर एक लड़की से बलात्कार और उसे सिगरेट से जलाने के आरोप थे। अप्रैल में प्रधानमंत्री से भेंट के बाद सरला ने एक तरह से दिल्ली में ही डेरा डाल दिया। 'माया' सूत्रों के अनुसार अप्रैल में प्रधानमंत्री से भेंट के बाद वह अकेले या लड़कियों अथवा नेताओं की टोली के साथ प्रधानमंत्री से हर हफ्ते-पखवाड़े मिलती रहीं। जाहिर है कि पचौरी-ठाकुर नेतृत्व के खिलाफ सरला मिश्रा की सक्रियता अर्जुन गुट से छिपी नहीं रही। पहले अर्जुन गुट के लोग सरला को विद्याचरण शुक्ल के गुट में गिनते थे और उसके नाम का इस गुट ने विरोध भी किया था, लेकिन पचौरी लाबी को मात देने की मीयत से इस गुट ने इस

गंदी राजनीति का परिणाम : तेजाब से झुलसा लकी

निगम की ओर से
भव्य सेवा-निवृत्ति
उपहार

30 वर्ष की आयु से
केवल **50 रुपये** प्रतिमाह
का प्रीमियम भरिए और
60 वर्ष की आयु से पाइए—
920* रुपये प्रतिमाह की आजीवन वार्षिक वृत्ति
तथा 1,10,098* रुपये
अपने परिवार के लिए !

जीवनधारा

निगम का नया डिफ़र्ड एन्युटी प्लान

लीजिए पेश है आजीवन सुरक्षा की गारंटी के लिए एक अनोखी योजना, अपनी कमाई के दिनों में नाम मात्र प्रीमियम अदा कीजिए और अवकाश ग्रहण के बाद भारी लाभ कमाइए—सेवा निवृत्ति के सभी वर्षों के दौरान हर वर्ष एक साथ बारह मासिक चेक पाइए. इसके अतिरिक्त आपके परिवार को मिलेगा बोनसों सहित ग्रॉस इन्स्योरेंस वैल्यु एलीमेंट (जी.आई.वी.ई)

वार्षिक वृत्ति शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर आपके प्रीमियम ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे (यदि आपने तीन वर्ष से अधिक प्रीमियम अदा किए हों तो).

20 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति निगम की जीवनधारा योजना का लाभ उठा सकता है. इस आकर्षक योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए निगम के स्थानीय मंडल कार्यालय से सम्पर्क करें.

1200 रुपये की
वार्षिक सेवा-निवृत्ति आय के लिए तालिका

प्रवेश के समय आयु (वर्ष)	आस्थगित अवधि (वर्ष)	वार्षिक प्रीमियम (रु)	जी.आई.वी.ई. (रु)
25	30	65.20	11,964
25	35	38.90	11,958
30	25	110.70	11,964
30	30	65.20	11,958
35	20	193.80	11,964
35	25	110.60	11,958
40	15	355.90	11,964
40	20	193.70	11,958
45	10	724.40	11,964
45	15	355.80	11,958

भारतीय जीवन बीमा निगम
बीमा कराइए और सुरक्षित हो जाइए.

* तथा बोनस

daCunha/LIC/230/87

दमदार मोहरे पर दांव लगाने की ठानी। जानकार सूत्रों के अनुसार, सरला मिश्रा अर्जुन सिंह से पहले-पहल कपूरथला हाउस में मिलीं और बाद में ५, तुगलक रोड में उनकी कई मुलाकातें हुईं। श्री सिंह ने सरला को कोई सलाह दी या नही, कहा नहीं जा सकता, किंतु सरला मिश्रा का अभियान दिनोंदिन जोर पकड़ता गया। सूचनाओं पर भरोसा करें, तो दिग्विजय सिंह, अजीत जोगी और सुभाष यादव जैसे सांसदों की जोड़ी पृष्ठभूमि में लगातार सक्रिय रही। गड़े मुर्दे उखाड़े गये और पचौरी-ठाकुर और उनके सहयोगियों के कथित आपराधिक मामलों के खर्रे के खर्रे तैयार कर आलाकमान को थमाये गये।

कार्रवाई : यह वह दौर था, जब सरला मिश्रा पदच्युत होने के कारण बुरी तरह बिफरी हुई थीं और प्रतिद्वंद्वी को येन-केन-प्रकारेण मात देने की फिराक में थीं। पचौरी की कर्मठता और सच्चरित्रता का लोहा वह भी मानती थीं, लेकिन राजनीतिक समीकरणों ने दोनों को आमने-सामने ला खड़ा किया। पचौरी गुट की नजरों में सरला पद की लालसा में कुछ भी कर गुजरने पर उतारू थीं और सरला की नजरों में न तो महत्वाकांक्षी होना बुरा था और न ही लड़ाई में तरह-तरह के हथियारों का इस्तेमाल गलत था। लकी कांड के कारण अपयश और लानत मलामत के शिकार युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत थी कि सरला मिश्रा को कोई शिकायत थी, तो उसे उन्हें पहले प्रांतीय नेतृत्व के सामने लाना चाहिए था और अगर उन्हें वहां न्याय नहीं मिलता, तो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के पास गुहार करनी चाहिए थी। यह भी जानकारी मिली कि ठाकुर ने जबलपुर शहर युवक इंका में सहसचिव पद पर मनोहर चंसोरिया की नियुक्ति जिलाध्यक्ष प्रेम दुबे की सिफारिश पर की थी, जो युवक कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में सरला मिश्रा के साथ थे। इन्हीं दिनों 'माया' ब्यूरो को लोकसभा सदस्य ले० कर्नल अजय नारायण मुशरान के अरुण नेहरु को ३१ मई, १९८५ को लिखे पत्र की फोटो प्रति भी मिली, जिसमें श्री मुशरान ने चंसोरिया को उपयुक्त दायित्व सौंपने की सिफारिश की थी। कहना न होगा कि सारी सूचनाएं अलग-अलग जरियों से आलाकमान तक पहुंचती रहीं। चुपचाप सुरंगें खोदने और पलीते लगाने का खेल चलता रहा और अगस्त तक हालात ऐसे बन गये थे कि पचौरी-ठाकुर लाबी के सामने ढेर सारी मुश्किलें खड़ी हो गयी थीं। इस बीच अ०भा० युवक कांग्रेस—इ के महामंत्री जगमीत सिंह बरार भोपाल जाकर गुटीय लड़ाई का जायजा ले आये थे। सितबर के पूर्वार्द्ध में सरला मिश्रा और उनके साथियों—बृजमोहन श्रीवास्तव, प्रेम दुबे, अनवर खान के बहाल होने की देर थी कि पचौरी विरोधी शिविर में हर्षोल्लास छा गया और पचौरी-ठाकुर सकते में आ गये। बताते हैं कि सरला समेत युवा नेताओं की बहाली में श्री बरार ने अहम भूमिका निभायी।

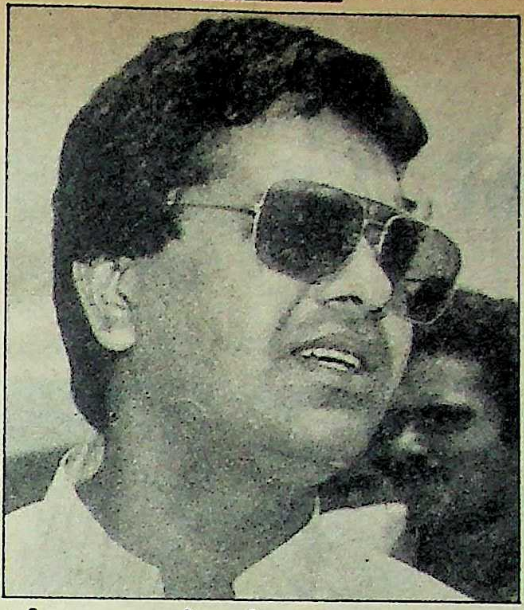

अर्जुन गुट का समर्थन : मुकेश नायक

कुमारी मिश्रा की उपाध्यक्ष पद पर बहाली तो हुई, लेकिन वह और उनके साथी अधिक दिनों तक इन पदों पर रह नहीं सके। काबिज नेतृत्व ने जवाबी दांव चला और शीघ्र ही अध्यक्ष ठाकुर को छोड़-पूरी प्रांतीय कमेटी भंग कर दी गयी। शह और मात का यह खेल ज्यों-ज्यों तेज होता गया, भोपाल और दिल्ली में गतिविधियां तेज होती गयीं। सितंबर-अक्टूबर में भोपाल और अन्य जगहों के युवक दिल्ली जाकर पक्ष-विपक्ष में मोर्चे बांधते रहे। अध्यक्ष ठाकुर और पूर्व उपाध्यक्ष सरला का द्वंद्व इतना तीखा था कि बताते हैं कि श्री ठाकुर ने तत्कालीन अध्यक्ष आनंद शर्मा से यहां तक कह डाला था कि वह सरला मिश्रा को किसी भी कीमत पर सहन या 'एडजस्ट' नहीं करेंगे भले ही उन्हें अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ जाये? इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि आयु सीमा पार कर जाने के कारण सांसद सुरेश पचौरी ने अ०भा० युवक कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इससे यह संभावना भी उठ खड़ी हुई कि श्री ठाकुर को भविष्य में श्री पचौरी के स्थान पर अखिल भारतीय युवक कांग्रेस का महासचिव बनाया जा सकता है। इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों में होड़ तेज हो गयी। दिलचस्प बात यह हुई कि अर्जुन-दिग्गी गुट ने सरला मिश्रा के जरिये लड़ाई तो लड़ी, लेकिन अध्यक्ष पद के दावेदार के तौर पर विधायक मुकेश नायक का नाम आगे बढ़ाया। सिंधिया समर्थकों ने अशोक शर्मा व राजेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया। पचौरी समर्थकों ने विधायक सत्यदेव कटारे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पचौरी, सिंधिया व वोरा एक ही धुरी के सदस्य हैं, मगर हालात की पेचीदगी को देखते हुए एक और नाम राजकुमार पटेल वोरा समर्थकों की ओर से पैनल में जुड़ गया। अर्जुन गुट के समर्थन के भरोसे भोपाल थोक उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष बृजमोहन श्रीवास्तव भी मैदान में आ गये। इधर उनका मैदान में आना था कि भोपाल के एक सांध्य दैनिक ने श्रीवास्तव की पौन लाख रुपए की कथित हेराफेरी का मामला उछाल दिया। सांसद रामेश्वर नीखरा की उमंगों ने पेंग मारी, तो वह काकू भाई के एक चहेते युवा नेता के लिए कोशिशों में जुट गये। उल्लेखनीय है कि काकू भाई के टिकट के लिए वितरण के समय पचौरी अर्जुन सिंह तक से झगड़ पड़े थे। सरला मिश्रा अपने दम पर दौड़ में थीं और आज भी हैं। इस अभियान में उन्हें सेवा दल के अखिल भारतीय अध्यक्ष तारिक अनवर का भी समर्थन प्राप्त है।

नेपथ्य में भागदौड़ और गोटियां बिठाने का खेल जोरों पर है। लोगों की उत्सुकता यह देखने की है कि द्वंद्व में कौन सा पक्ष जीतता है।

आलाकमान को दिये ज्ञापनों में पचौरी विरोधियों ने पचौरी पर युवक कांग्रेस को अपना राजनीतिक चारागाह बनाने का आरोप लगाया है। इस बारे में युवा नेताओं से बात हुई, तो भिन्न-भिन्न बातें सामने आयीं। पचौरी से जुड़े पत्रकार नेता मधुकर द्विवेदी, जो युवक कांग्रेस के एक प्रकोष्ठ से भी संबद्ध हैं, ने कहा कि बहुत से नेता पचौरी की लोकप्रियता, सूझबूझ और कर्मठता से ईर्ष्या रखते हैं और इन लोगों के सारे अभियान का उद्देश्य मात्र 'पद' हथियाना है। यह बात कई लोगों ने मानी कि एडवोकेट साजिद अली के हटने के बाद अल्पसंख्यक तबका यूथ कांग्रेस से कटा है। भंग कमेटी के महामंत्री रायपुर के मोहम्मद अकबर ने कहा कि पुनर्गठन में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कुछ नेता दिग्गज नेताओं की दखलंदाजी से भी क्षुब्ध दिखे। पदाधिकारियों की सूची देखने से यह तथ्य उजागर होता है कि पचौरी-ठाकुर ने अन्य नेताओं के नुमाइंदों को भी युवा संगठन में ठौर दिया है। छिंदवाड़ा में प्रदीप सक्सेना, रायगढ़ में संजय सिंह, राजनांदगांव में विजय शाह और अजय सिंह परिहार, सीधी में नंद कुमार सिंह व रीवा में कुशल सिंह, रायपुर में महेश शर्मा, बिलासपुर में आशीष ठाकुर, दुर्ग में अरुण वोरा विभिन्न नेताओं के नुमाइंदे हैं और जिला इकाइयों में अध्यक्ष-पद को सुशोभित कर रहे हैं।

जहां तक पचौरी समर्थकों व विरोधियों की तुलना का प्रश्न है, साधनों की दृष्टि से पचौरी विरोधी समर्थकों पर भारी बैठते हैं। आनंद शर्मा के बाद कामत के अ०भा० युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से भी समीकरणों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। बहरहाल, नेपथ्य में भागदौड़ और गोटियां बिठाने का खेल जोरों पर है। लोगों की उत्सुकता यह देखने की है कि द्वंद्व में कौन-सा पक्ष जीतता है, किंतु यह संभवतः अधिक महत्वपूर्ण है कि युवक कांग्रेस लोक कल्याण व सार्थक परिवर्तन का रचनात्मक मंच कब और कैसे बनता है?

छाया : बिम्ब स्टूडियो —सुधीर सक्सेना

श्रीमती सुमन लता सेठिया

अदालत से मौत की फरियाद

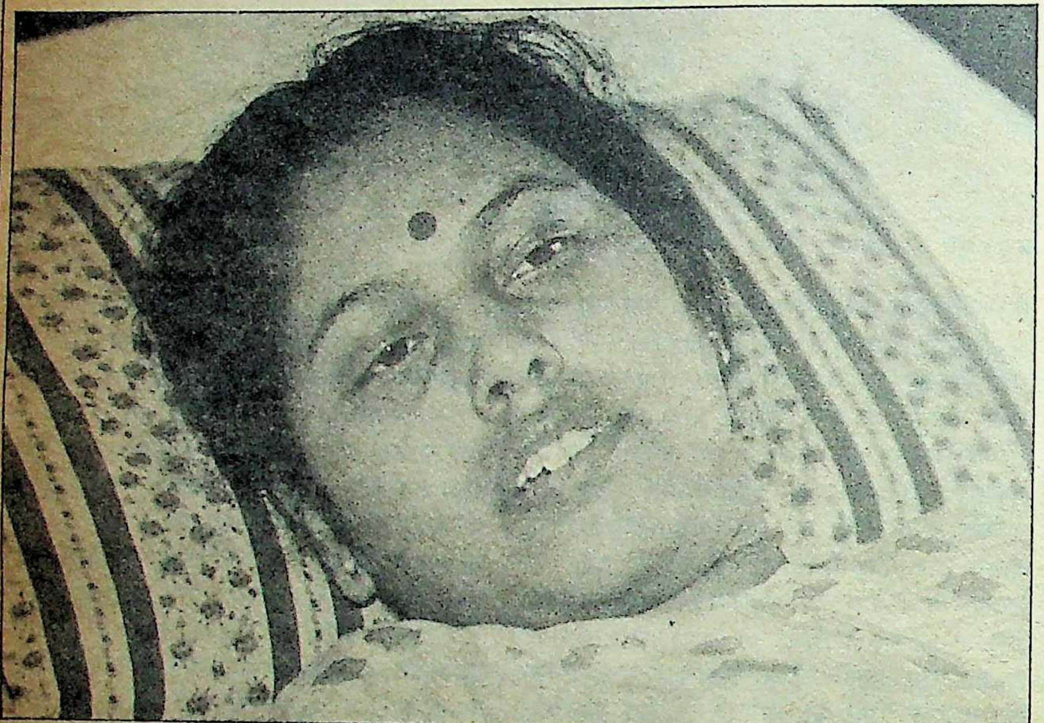

मौत या मुआवजा ? : सवाई मार्नसिह चिकित्सालय में लकवाग्रस्त श्रीमती सुमन सेठिया

राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में यह पहला प्रकरण है, जिसमें वादी ने चैन की मौत की फरियाद की है। २४ वर्षीया सुमन सेठिया के परिवार नियोजन आपरेशन में सरकारी डाक्टरों से ऐसी लापरवाही हुई कि उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वह पिछले दो वर्षों से अस्पताल में अपने दो शिशुओं के साथ ऐसी हालत में पड़ी हैं कि बड़ी मुश्किल से हिलडुल पाती हैं। इलाज और परवरिश के लिए उनके पास धन नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय से फरियाद की है कि या तो उन्हें इतना मुआवजा दिया जाये कि जिंदगी बसर कर सकें या उन्हें पीड़ारहित मौत दे दी जाये। प्रस्तुत है, श्रीमती सुमन सेठिया की व्यथा कथा :

‘‘मैंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के सिर्फ दस दिन बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रचार नारे—छोटा परिवार, सुखी परिवार’ को देशहित में उचित मानकर गर्भ निरोधक आपरेशन करवाया। एक अगस्त, १९८५ को चूरू जिले के सरदार शहर स्थित सरकारी अस्पताल में आपरेशन हुआ। जल्दबाजी में किये इस आपरेशन के दौरान मेरी हृदयगति रुकी। शल्य चिकित्सक ने मेरी हृदयगति चालू कर अपने को कत्ल के इलजाम से तो बचा लिया, पर इसका मेरे मस्तिष्क पर ऐसा आघात लगा कि आज मैं मात्र मांस का लोथड़ा बनकर रह गयी हूं। मेरे दोनों हाथ, दोनों पांव, जुबान तथा शरीर के अंग लकवाग्रस्त हैं। मैं अपनी सारी क्रियाओं के लिए आश्रित हूं।’’

२४ अक्तूबर, १९८७ को उक्त भाषा में लिखा पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा को प्राप्त हुआ। सुखी परिवार की लालसा से पीड़ित श्रीमती सुमन सेठिया दो साल से भी ज्यादा समय से पीड़ा भुगत रही हैं। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि उनके साथ हुए हादसे के लिए राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है। यह संयोग ही था कि जनता सरकार के जमाने के पूर्व उद्योगमंत्री एवं पेशे से वकील सूर्य नारायण चौधरी जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अपने पक्षाघात का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने श्रीमती सुमन लता सेठिया की दयनीय हालत देखी, तो जिज्ञासावश मर्ज की वजह जाननी चाही। श्रीमती सुमन के ५६ वर्षीय ससुर चन्दनमल ने श्री चौधरी को सारा किस्सा बताया। वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद एडवोकेट श्री चौधरी ने श्रीमती सुमन की ओर से एक पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा को लिखाया।

उच्च न्यायालय से अपील : इस पत्र में दर्ज किया गया कि आपरेशन के बाद श्रीमती सुमन चार दिन तक सरदार शहर के अस्पताल में बेहोश रहीं। वहां से इलाज़ के लिए उन्हें जयपुर के सवाई मानसिह चिकित्सालय में भेजा गया जहां तीन माह उन्होंने बेहोशी में काटे। बेहोशी टूटने पर अस्पताल के चिकित्सकों ने घोषित किया कि श्रीमती सुमन के मस्तिष्क को आघात लगा है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर की सारी क्रियाएं मस्तिष्क नियंत्रण से मुक्त हो गयी हैं।

मुख्य न्यायाधीश को श्रीमती सुमन ने बताया कि जब उन्होंने गर्भ निरोधक आपरेशन करवाया, तो उनके नवजातशिशु (कन्या) की आयु मात्र दस दिन थी, जबकि अन्य सन्तान (पुत्र) की उम्र मात्र तीन साल। दोनों बच्चों की देखभाल करने में श्रीमती सुमन तभी से लाचार हैं। उनके पति सुशील कुमार असम में व्यवसाय कर मात्र हजार डेढ़ हजार रुपए कमा पाते हैं, जिसमें परिवार के लिए विशेष कुछ भेज पाना संभव नहीं होता। इधर तेरह माह से चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार केवल अस्पताल में मुफ्त रिहायश और दवाओं के सहयोग के अलावा कोई अन्य सहायता नहीं दे रही है।

दसवीं पास श्रीमती सुमन ने न्यायाधीश से निवेदन किया, ‘‘मैं बिना किसी सहारे और सहायता के अपना जीवन नहीं चला सकती। मेरा कसूर तो बस इतना ही है कि मैं केन्द्रीय व राज्य सरकार के नारे—‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’ पर भरोसा कर, ‘छोटे से आपरेशन से कोई खतरा नहीं’ जैसी बात मानते हुए परिवार नियोजन को राष्ट्रीय कर्तव्य मान आपरेशन करा बैठी। अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा खर्चा तब तक राज्य व केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाये, जब तक मैं स्वावलम्बी न बन जाऊं और मेरे छोटे-छोटे बच्चों पर रहम खाकर उचित कार्यवाही करें, जिससे मुझे मेरा हक व दोषी को दण्ड मिल सके।’’

श्रीमती सुमन के इस पत्र को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा ने

जनहित याचिका के तहत स्वीकार किया। आठ सितम्बर, १९८६ को मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान सरकार व निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को याचिका का जवाब देने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। राजस्थान सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि श्रीमती सुमन सेठिया के आपरेशन के दौरान निश्चेतक (ऐनिस्थेटिस्ट) ने फोर्टविन व काम्पोज इंजेक्शन से उन्हें निश्चेत किया, जबकि सुमन सेठिया और उसके परिवारवालों का कहना है कि आपरेशन थियेटर में गर्भ निरोधक आपरेशन करनेवाले डाक्टर एस०के० कौशिक के अलावा अन्य कोई डाक्टर नहीं था। बहरहाल, सरकारी जवाब के अनुसार आपरेशन के दौरान श्रीमती सुमन सेठिया के दिल की धड़कन लुप्त होने जैसी स्थिति में आयी, जिसे दिल की मालिस कर सामान्य किया गया। सरकारी जवाब में बाद की स्थितियों की गम्भीरता को गौण माना गया। मसलन यह नहीं माना गया कि वह लगातार निश्चेत रहीं, बल्कि चिकित्सा करने की बात कही गयी। यानी चिकित्सा के तहत सरदार शहर के पास के बड़े शहर बीकानेर से डा० धनखड़ को बुलाया गया, फिर भी हालत नहीं सुधरी, तो जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया गया। जयपुर के अस्पताल में श्रीमती सेठिया की चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली से न्यूरोलोजिस्ट (तंत्रिका विशेषज्ञ) डा० एम०सी० माहेश्वरी को बुलाया गया। सरकारी जवाब में कहा गया कि तब से श्रीमती सुमन सेठिया और उनके रिश्तेदारों को हर तरह की सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं।

सरकारी जवाब में यह मानने से साफ इनकार कर दिया गया कि आपरेशन के दौरान किसी तरह की लापरवाही बरती गयी। हिन्दी-भाषी प्रदेश राजस्थान की सरकार की ओर से अंग्रेजी में दिये जवाब में, सरकारी वकील ने श्रीमती सुमन सेठिया की प्रार्थना को याचिका के काबिल न मानते हुए मय खर्च (विद कोस्ट) रद्द करने की प्रार्थना की।

दोषी कौन? : १५ फरवरी, १९८७ को राजस्थान सरकार की ओर से दिये जवाब के विपरीत एडवोकेट सूर्य नारायण चौधरी ने श्रीमती सुमन सेठिया की ओर से संविधान की धारा-२२६ व धारा-३२ के अन्तर्गत आधारभूत मौलिक अधिकारों के तहत शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका तर्क था कि परिवार नियोजन के लिए प्रचार करनेवाली सरकार एवं उसके प्रेरक कर्मचारी ने श्रीमती सेठिया को प्रेरित किया था। राजस्थान सरकार ऐसी किसी क्षतिपूर्ति से इनकार कर रही थी, जबकि दूसरी ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष आदेश देकर श्रीमती सुमन सेठिया की आपरेशन के बाद स्थिति की जांच करवा रही थी। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट सचिव को उक्त जांच रिपोर्ट १६ अप्रैल, १९८७ को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट को सवाई मानसिंह चिकित्सालय के तीन वरिष्ठ विशेषज्ञों ने तैयार किया था। रिपोर्ट में माना गया कि श्रीमती सुमन सेठिया गर्भ निरोधक आपरेशन से पूर्व स्वस्थ थीं। इसमें खुलासा किया गया कि आपरेशन के बाद जब दो घण्टे बाद भी श्रीमती सेठिया की चेतना नहीं लौटी, तो पांच दिन उन्हें सरदार शहर के चिकित्सालय में रखा गया और बाद में जयपुर लाया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में श्रीमती सुमन सेठिया को तीन माह बाद चेतना लौटी, तो शरीर के चारों हिस्से (लिम्ब) पक्षाघात से पीड़ित थे। आवाज गड़बड़ थी। अपनी हालत पर श्रीमती सेठिया कभी रोतीं, तो कभी हंसती थीं।

परिवार-नियोजन ने घर उजाड़ दिया :श्रीमती सुमन की देखभाल करती सास श्रीमती रत्ना देवी

विशेषज्ञों को यह ज्ञात नहीं हो सका कि श्रीमती सुमन सेठिया को निश्चेत करने के लिए कैसा एनेस्थीसिया दिया गया, जबकि न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में फोर्टविन, काम्पोज तथा जायलोकिन देने की बात कही गयी थी। शल्य-चिकित्सक प्रोफेसर डाक्टर ओंकार सक्सेना, मेडीसन के प्रमुख एवं प्रोफेसर डा० विश्वमित्र भण्डारी और निश्चेतक प्रोफेसर आई०पी० गर्ग ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में दर्ज किया है कि मरीज (श्रीमती सुमन सेठिया) को निश्चेत करने के साथ ही उसके केन्द्रीय तंत्रिका सिस्टम में गड़बड़ हो गयी। जिसके परिणामस्वरूप शल्य क्रिया के दौरान और पूर्व में दिल की धड़कन बन्द हुई और बात में पुनः दिल ने काम करना प्रारम्भ किया। यानी, सरकार की कानूनी भाषा दूसरी थी और संवेदना की रिपोर्ट कुछ अलग ही थी।

बिना दस्तखत का फैसला : इस मामले में मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा के आदेशों के अनुसार दो न्यायाधीशों की पीठ को इस याचिका की सुनवाई करनी थी। सुनवाई के दौरान श्रीमती सुमन सेठिया के वकील सूर्य नारायण चौधरी को आश्चर्यजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। वह न्यायाधीशों के समक्ष श्रीमती सुमन सेठिया का पक्ष रख ही रहे थे कि पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश महेन्द्र भूषण ने राजस्थान सरकार के जवाब को खारिज करते हुए फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने श्रीमती सुमन सेठिया की स्थिति को दयनीय करार दें, उनकी जीवन अवधि पचास वर्ष मानी। इस मानने के साथ यह भी माना कि इस अवधि में वह विकलांग ही रहेंगी और उस स्थिति में उन्हें हमेशा एक देखभाल करनेवाले सहयोगी की जरूरत होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए न्यायाधीश ने अपने फैसले में राज्य सरकार को श्रीमती सुमन सेठिया को पचास हजार रुपए हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिये।

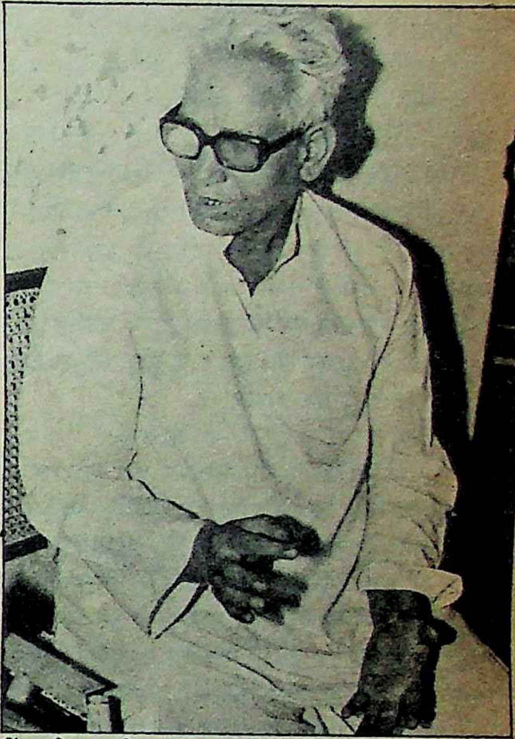

जिंदगी भर देखभाल करूंगा : श्रीमती सुमन के ससुर चन्दनमल

इस आदेश के सम्बन्ध में वकील श्री चौधरी ने न्यायालय से कुछ निवेदन करना चाहा, पर न्यायाधीश महेन्द्र भूषण इतनी जल्दी में थे कि अपने द्वारा दिये फैसले पर हस्ताक्षर किये बगैर चल दिये। अगले दिन न्यायाधीश अपने दिल का इलाज कराने अमरीका चल दिये। इस स्थिति में निर्णय का कोई अर्थ नहीं रह गया। श्रीमती सुमन सेठिया अथवा राजस्थान सरकार को उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती थी, जब तक विद्वान न्यायाधीश महेन्द्र भूषण विदेश से लौटकर उस पर हस्ताक्षर न करें ।

मौत की फरियाद : तंग आकर श्रीमती सुमन सेठिया ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना में अपनी दारुण स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमती सुमन सेठिया ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले 'एस०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया' का हवाला दिया। यह फैसला एक्सीडेन्ट जर्नल क्लेम, १९८७ के अप्रैल अंक की पृष्ठ संख्या ३८६ में दर्ज है। इस

फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशात्मक उत्तरदायित्व न्यायालयों का माना है। श्रीमती सुमन सेठिया की प्रार्थना में तर्क है कि विद्वान न्यायाधीश महेन्द्र भूषण ने उनके वकील की नजीर सुने बगैर पचास हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने का फैसला लिखवा दिया, जबकि ऐसे मामले में पचास लाख रुपए मिलने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा को दिये प्रार्थना पत्र में श्रीमती सुमन ने आगे कहा है कि विद्वान न्यायाधीशों ने उनकी (श्रीमती सुमन सेठिया) जीवन अवधि पचास वर्ष और मानी है। इस अर्थ में प्रति वर्ष हजार रुपए होता है जो एक माह में लगभग ८४ रुपए सहयोग राशि के रूप में बनते हैं। एक विकलांग ८४ रुपए महीने में कैसे गुजारा करेगी?

श्रीमती सेठिया की ओर से लिखे गये प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया है कि उनकी सम्पूर्ण विकृति आपरेशन के कारण हुई है, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसी स्थिति में उन्हें जिन्दा रहने के लिए पचास हजार की जगह पचास लाख रुपए राज्य सरकार से दिलवाये जाने चाहिए या फिर नारकीय जीवन से छुटकारे हेतु दर्द विहीन मौत के निर्देश दे देने चाहिए।

हादसा क्यों हुआ? : ७ सितम्बर, १९८७ को प्रस्तुत किया गया, यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में 'मर्सी डैथ' की याचनावाली पहली याचिका होगी। 'माया' ने उन कारणों व सवालों को टटोलने की चेष्टा की है जिनकी वजह से श्रीमती सुमन सेठिया को मौत की याचना करनी पड़ी है। यह सच है कि श्रीमती सुमन सेठिया की विकलांगता का कारण आपरेशन के दौरान बरती गयी लापरवाही है, पर लापरवाही हुई क्यों? इस सवाल का जवाब राजस्थान के विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों की ऐसोसियेशन के पदाधिकारी देते हैं। निजी कारणों से ये पदाधिकारी अपना नाम नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि इस तरह की जल्दबाजी के लिए राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं? सरकार हर वर्ष परिवार नियोजन के अपने लक्ष्य निर्धारित कर देतीं है। मसलन १९८७-८८ में इस कार्यक्रम के तहत नसबन्दी का लक्ष्य तीन लाख और लूप प्रविष्ठि का एक लाख, बीस हजार है। इस वर्ष सितम्बर तक नसबन्दी के मात्र ३९,७७० आपरेशन हुए थे। अब बाकी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 'विशेष प्रयास' किये जायेंगे। मसलन इस क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों को स्थानान्तरण, निजी सी०आर० में विपरीत टिप्पणियों इत्यादि का भय दिखाया जायेगा। ऐसी स्थिति में चिकित्सक जल्दबाजी करेगा जो इस व्यवसाय में वाजिब नहीं है। इन पदाधिकारियों का कहना है कि परिवार कल्याण का काम जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए। बहरहाल, सरकार अपनी उपलब्धियों की धाक जमाने के लिए ऐसा करती है, जिसमें श्रीमती सुमन सेठिया के जैसे हादसे हो जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि उपलब्धियों की वाहवाही हासिल होती है, राज्य सरकार को और हादसा होने पर मरीज और सरकार जिम्मेदार ठहराते हैं, केवल डा० एस०के० कौशिक जैसे लोगों को।

श्रीमती सुमन सेठिया पिछले दो वर्षों से जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं, पर राज्य सरकार की परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती जकिया इनाम ने उन्हें जाकर देखने क़ी ज़िम्मेदारी आज तक नहीं निभायी है। जब 'माया' ने इस सन्दर्भ में उनसे बात करने के लिए सम्पर्क की चेष्टा की, तो ज्ञात हुआ कि मंत्रीजी अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक गयी हुई हैं। बहरहाल, स्थानीय समाचार पत्र के एक संवाददाता से उन्होंने श्रीमती सुमन सेठिया के बारे में चिता व्यक्त की है और फरमाया है, "सरकार उनकी हर तरह से मदद करेगी।" मदद करने का जो रवैया रहा है, उसे केवल इससे समझा जा सकता है कि श्रीमती सुमन सेठिया को राहत के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं।

श्रीमती सुमन का नजरिया : 'माया' ने श्रीमती सुमन सेठिया से सवाई मानसिंह चिकित्सालय के काटेज वार्ड के कमरा नं० २४ में मुलाकात की। अब उनकी सेहत में इतना परिवर्तन जरूर है कि उन्हें बैठाया जाये, तो बिस्तर पर बैठ सकती हैं, पर शरीर का कोई भी हिस्सा कभी भी उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहयोगी की जरूरत होती है और सहयोगी हैं, वृद्ध सास-ससुर। उनका पांच साल का लड़का, दो वर्ष की बेटी मां का मन बहलाते नजर आते हैं। कितना अजीब दृश्य था, जहां बच्चों को मां का प्यार मिलना चाहिए, वहां बच्चे मां को अपना प्यार दे रहे थे। 'माया' ने जब उनसे पूछा कि अब आप कैसी हैं, तो उनका अटक-अटककर जवाब था, "हां...ठीक...हूं। भगवान ... उठा...ले...तो...अच्छा...हो।" चौबीस वर्षीय श्रीमती सुमन सेठिया इससे आगे और कुछ नहीं कह पातीं। जब उनसे पूछा गया कि अब आप न्यायालय से क्या चाहती हैं? उनका कहना था या...तो...मौत...दे...दो...या...फिर...(पैसे) दो।"

बेसहारा : श्रीमती सेठिया की पुत्री

श्रीमती सुमन सेठिया की वृद्धा सास श्रीमती रत्ना देवी से जब 'माया' ने पूछा कि आपका पुत्र कहां है? उनका कहना था, "अब एक ही तो कमानेवाला रह गया है, असम में अपना धंधा कर कुछ मदद भेजता है। फिर सुमन सेठिया की ओर इशारा कर कहती हैं, "इसके ससुर तो उसी दिन से कलकत्ता में अपना काम छोड़कर आ गये, जब सुना कि इसकी (सुमन सेठिया) यह हालत हो रही है। बस अब एक लड़का कमाता है।" जब उनसे कहा गया कि अब तो न्यायालय ने राज्य सरकार को पचास हजार रुपए क्षतिपूर्ति के देने के आदेश दिये हैं? उनका कहना था, "आदेश पर दस्तखत तो किये नहीं। जब से रिश्तेदारों ने सुना है, मदद में दिये पैसे वापस मांगने शुरू कर दिये।" श्रीमती रत्ना सेठिया नाराज थीं। उनका कहना था, "आपरेशन ने हमारा घर उजाड़ दिया। मुझे बहू के साथ-साथ बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। बच्चों को न अच्छा खाने को मिलता है, न पढ़ने को। बस मरीजों के बीच भटकते रहते हैं।"

आंखों के रोग से परेशान श्रीमती सुमन सेठिया के ससुर चन्दनमल से 'माया' ने जानना चाहा कि वह अपनी बहू की सेवा करते ऊबे नहीं? उनका जवाब था, "मेरी बेटी की यह हालत होती, तो क्या मैं ऊबता? मैं तो जिन्दगी भर इसकी देखभाल करूंगा।" सरकारी सहयोग के सम्बन्ध में उनका कहना था कि राज्य सरकार के पूर्व स्वास्थ्यमंत्री हीरालाल देवपुरा ने सारे मामले में भारी मदद की। उन्हीं के आदेशों से निःशुल्क काटेज और काफी हद तक दवाएं प्राप्त होती हैं, वरना चिकित्सकों ने तो पांच माह बाद मरीज को घर ले जाने के लिए कह दिया था। सारे मामले में एडवोकेट एवं जनता सरकार में उद्योग मंत्री रहे सूर्य नारायण चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 'माया' ने उनसे जब साक्षात्कार लेना चाहा, तो उन्होंने यह कहकर चुप्पी साध ली—"मुझसे मत पूछो, अपनी आंखों से देखो और लोगों को बताओ कि प्रजातन्त्र के लाभ उन्हीं लोगों को हासिल होते हैं, जो सक्षम हैं। गरीब की सुननेवाला कोई नहीं है। राजनेताओं की तकलीफ को तो ह्यूस्टन के अस्पताल में ले जाकर दूर करने में लाखों रुपए खर्च किये जाते हैं, पर जिस गरीब का पैसा है, उसें जीने के लिए भी मुआवजा देने में रोड़े अटकाये जाते हैं।" निश्चित रूप से श्रीमती सुमन सेठिया के साथ प्रशासन और सरकार का रवैया शर्मनाक है, जिसे सुनकर नहीं देखकर महसूस किया जा सकता है। श्रीमती सुमन सेठिया ने बम्बई के एक ५९ वर्षीय एडवोकेट रामानंद का उदाहरण भी दिया है। एक दुर्घटना में उनके शरीर का आधा अंग बेकार हो जाने पर न्यायालय ने उन्हें मुआवजे के रूप में २७ लाख रुपए देने का आदेश दिया था। अब देखना यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय श्रीमती सुमन सेठिया की प्रार्थना पर क्या निर्णय देता है?

—ओम सैनी

छाया : गोपाल संगर

शोध संस्थान या कलह संस्थान

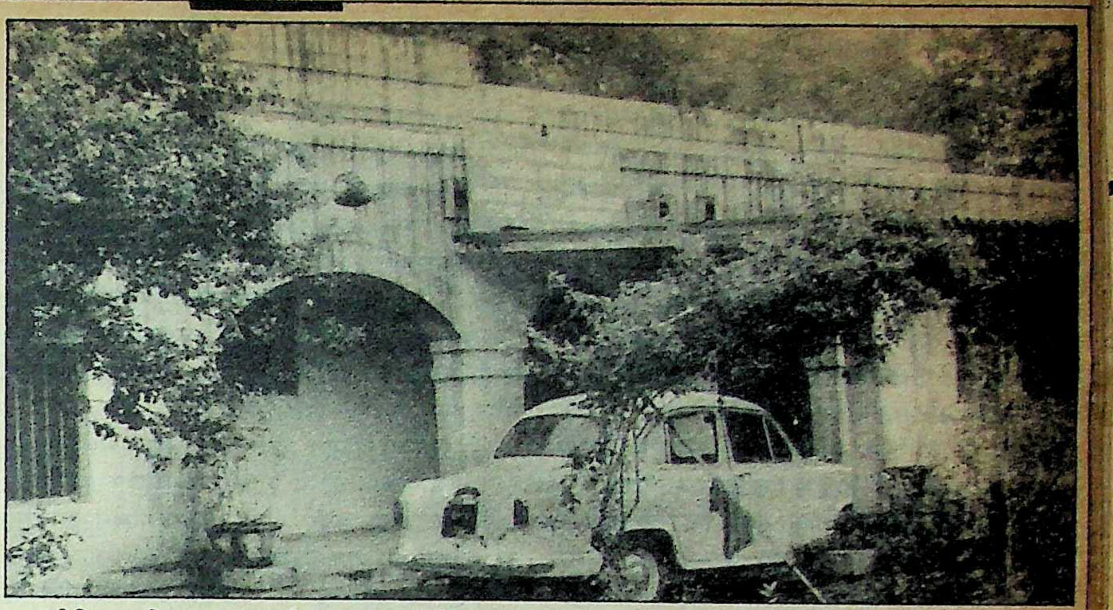

राजनीति का शिकार: 'जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान' का कार्यालय

आर्थिक-सामाजिक विषयों पर मौलिक शोध के लिए १९५९ में स्थापित 'अनुग्रह नारायण समाज अध्ययन संस्थान' और राजनीतिक विषयों में शोध करने का उद्देश्य लेकर १९७७ में स्थापित 'जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थानं' इन दिनों अपने मूल उद्देश्यों से भटककर किस दुर्दशा के शिकार हो गये हैं कि इन्हें शोध संस्थानों की बजाय कलह संस्थान कहा जाने लगा है?

भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर राजेंद्र प्रसाद की अवधारणा के अंतर्गत आर्थिक-सामाजिक विषयों पर मौलिक शोध के मूल उद्देश्य को लेकर १९५९ में संस्थापित 'अनुग्रह नारायण समाज अध्ययन संस्थान' पटरी पर नहीं है।

संस्थान की दिनोदिन बिगड़ती हालत पर आंसू बहाते इसके कर्मचारी बताते हैं कि इससे बड़ी उम्मीदें बांधी गयी थीं। इसके पहले निदेशक प्रख्यात अर्थशास्त्री डा० गोरखनाथ सिंह थे। १९६६ में निदेशक का पद डा० ए०के० गुप्ता ने संभाला। डा० गुप्ता ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में संस्थान के पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों एवं पांडुलिपियों का संग्रह करवाया था। पर उनके जाते ही संस्थान में बदहाली के बादल मंडराने लगे। सितंबर, १९८५ से तो हालात बद से बदतर होते चले गये। कई बार ताले लटके। कुछ समय पूर्व संस्थान में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के समय अजीब स्थिति हो गयी थी जब शिमला विश्वविद्यालय से आये सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् डा० महेंद्र नारायण कर्ण ने सेमिनार का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया था। डा० कर्ण और उनके साथ कई अन्य विद्वान यह कहते हुए कि 'जब शोध शिक्षकं डा० शशि भूषण प्रसाद और अन्य सहयोगी जेल में हों, तब सेमिनार मुनासिब नहीं' चले गये थे। उस समय भी संस्थान-प्रशासन की आंखें नहीं खुली थीं।

संस्थान कर्मचारी संघ के एक अधिकारी का कहना है कि प्रारंभ में यह संस्थान बिहार सरकार के अधीन था। उसके बाद 'आटोनोमस बाडी' (स्वायत्तशासी) घोषित हो गयी। सरकार से हुए समझौते के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों को वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं बिहार सरकार के पटना सचिवालय स्थित तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों सी ही मिला करेंगी। हर तीन महीने पर 'बोर्ड आफ कंट्रोल' की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री करेंगे। पर विगत एक वर्ष से न तो बोर्ड की कोई बैठक हुई और न कर्मचारियों को घोषित सारी सुविधाएं ही मिल पायीं। प्रबंधन के साथ हुए समझौते को लागू करने की जब संस्थान कर्मचारी संघ ने मांग उठायी, तो संघ के संयुक्त सचिव चतुर्थ कर्मचारी बृज बिहारी राम को निलंबित कर दिया गया, जिस पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये थे। पटना के जिलाधिकारी मुख्तियार सिंह के हस्तक्षेप से २५ सितंबर, १९८५ से चल रही हड़ताल २२ दिसंबर, १९८५ को समाप्त हुई। हड़ताल-समाप्ति के समय हुआ समझौता, आज तक लागू नहीं हुआ। लिहाजा, कर्मचारी शीघ्र ही फिर हड़ताल पर जानेवाले हैं।

"हमारी लड़ाई विगत तीन वर्षों से जारी है, जारी रहेगी," यह घोषणा है, संस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डा० शशि भूषण प्रसाद की, जबकि प्रशासन और संघ का '३६' का रिश्ता है।

पीछे की कहानी : सन् १९८४ के अप्रैल माह में तत्कालीन निदेशक डा० दुर्गा नंदन सिंहा ने बाबू राम दरबान के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस पर तत्कालीन स्थानीय कम्युनिस्ट सांसद रामावतार शास्त्री ने निदेशक पर दबाव डाला। बताया जाता है कि नन्हकू यादव एवं इंद्रदेव यादव की उम्र मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करने में कम करवा दी गयी। नतीजतन कर्मचारियों का विरोध बढ़ा। जनवरी, १९८५ में तत्कालीन निदेशक डा० दुर्गा नंदन सिंहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लिहाजा, कर्मचारी संघ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ३ फरवरी से संगठित कार्रवाई का निर्णय लिया। डा० सिंहा को पुनर्नियुक्ति के बाद १३ फरवरी को, ३ फरवरी को दी गयी अपनी २८ सूत्री मांगों पर संघ ने इनसे विचार-विमर्श किया, लेकिन बातचीत टूट गयी। १५ फरवरी को इसके खिलाफ संघ ने सांकेतिक हड़ताल की और बोर्ड आफ कंट्रोल को अपना स्मरण पत्र देने की बात कही। इसी बीच संघ के इस कदम को रोकने के लिए बोर्ड की मीटिंग की जगह बदलकर सचिवालय कर दी गयी। करीब डेढ़ महीने तक संघ ने विरोध के स्वर जारी रखे। नतीजतन, ३० मार्च, १९८५ को प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक तीनों पक्षों को मिलाकर त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक २८ सूत्री मांगों की सूची में शामिल प्रथम २० मांगें जो प्रशासनिक ज्यादतियों और अधिकारियों के निरंकुश व्यवहार से संबंधित थीं, मान ली गयी थीं। दूसरी सात मांगें जो बोनस, वेतन, प्रोन्नति तथा महंगाई भत्ते की किश्तों वगैरह से संबंधित थीं, जल्दी ही बोर्ड द्वारा पूरी करवा देने का आश्वासन दिया गया। अंतिम मांग जो संस्थान की प्रजातांत्रिक संरचना से संबंधित थी, यानी निचले दरजे के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई निर्णय न लेते हुए समझौते के अंतिम परिच्छेद में एक 'इनबिल्ट मैकेनिज्म' बनाने की बात कही गयी।

इस समझौते के बाद दैनिक मजदूरी पर दो नियुक्तियां की गयीं। किंतु १२-१३ कर्मचारी जो पिछले सात-आठ वर्षों से कार्यरत थे, उन्हें तत्काल एक वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रखने की व्यवस्था की गयी, जबकि समझौते के अनुसार उन्हें सीधा 'कन्फर्म' कर देने की बात थी। उम्र सुधार के मामले में भी टालमटोल होती रही। मई में पुनः बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसके ८३ पेजीय एजेंडा में संघ के मामले को

विशेष महत्व नहीं दिया गया और उसके लिए एक 'उपसमिति' बनायी गयी। वित्त-आयुक्त, शिक्षा-आयुक्त व निद्रेशक द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों को उपसमिति में रखा गया। निदेशक के मनोनीत सदस्य थे—संस्थान के रजिस्ट्रार महेन्द्र प्रसाद पांडेय जो निरंकुश तानाशाह हैं और पिछले २० वर्षों से इस पद पर अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। इस अवधि में पटना विश्वविद्यालय में तेरह रजिस्ट्रार आये-गये, लेकिन श्री पांडेय डा० सच्चिदानंद सिन्हा सरीखे भूतपूर्व निदेशक एवं मौजूदा प्रोफेसर व मेसमेन तक को परेशान करने से बाज नहीं आते। पांडेय पिछले २० वर्षों से संस्थान में जिस स्थिति में स्थापित हैं, वह अपने आप में एक खोज का विषय है।

मामला उपसमिति को सुपुर्द कर दिये जाने के बाद १२ जुलाई को संघ ने ३१ जुलाई तक अपनी मांगों पर उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में ५ अगस्त से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। लिहाजा, २६ जुलाई को निदेशक तथा रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया कि बोर्ड संघ के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रुख अख्तियार कर रहा है। इसी बीच निदेशक डा० दुर्गा नंदन विदेश चले गये। उनके विदेश से लौटते ही २२ सितम्बर को कर्मचारियों ने काले झंडे से उनका स्वागत किया और २७ सितम्बर से आंदोलन तेज करने के संबंध में प्रशासन को सूचना दी। मामला अभी जोर पकड़ ही रहा था कि २५ सितम्बर को संस्थान के कर्मचारी बृज बिहारी राम को उम्र के मामले में फर्जी जानकारी देने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया। आरोप के अनुसार बृज बिहारी जो पिछले २० वर्षों से संस्थान में कार्यरत हैं, की उम्र ९ जुलाई, १९६६ को संस्थान में अस्थायी तौर पर काम करने के समय १९ वर्ष थी और उन्होंने अपनी जन्मतिथि ९ जुलाई, १९४७ लिखवाई। २६ दिसम्बर, १९६९ को स्टेट बैंक आफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक के पास जो अर्जी इन्होंने दी थी, उसमें इनकी जन्मतिथि २६ दिसम्बर, १९४९ है। पुन: २८ जुलाई, १९८० को इन्होंने संस्थान के पुस्तकालय अधीक्षक को जो अर्जी दी, उसमें जन्मतिथि २५ जनवरी, १९५१ दर्ज है। बृज बिहारी ने १९७९ में मैट्रिक पास करने के बाद पुस्तकालय अधीक्षक के पास अर्जी दी थी और इनके मैट्रिक के प्रमाण-पत्र में भी यही जन्मतिथि यानी २५ जनवरी, १९५१ दर्ज है।

'माया' द्वारा बृज बिहारी राम से इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि वह इस विषय के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहते। संघ के सूत्रों के मुताबिक ऐसा अज्ञानतावश ही हुआ है और यह आरोप निराधार है, क्योंकि बृज बिहारी ने सारी अर्जियां संस्थान के माध्यम से ही अन्य जगहों पर भेजी हैं। अगर वह फर्जी काम करना चाहते, तो ऐसा नहीं करते। दूसरा विशेष मुद्दा यह भी है कि इनकी नियुक्ति जिस पद पर की गयी, अर्जी और उसमें अंकित जन्मतिथि के आधार पर की गयी, वही जन्मतिथि इनके मैट्रिक के प्रमाण-पत्र में भी अंकित है तथा वही इनके सर्विस कार्ड बुक में भी। नतीजतन, इस मामले में फर्जी कार्रवाई का आरोप अगर संस्थान लगाता है, तो इनके पक्ष में सबूत मजबूत हैं जबकि संस्थान पर प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि संस्थान ने अर्जियों की जांच नहीं की।

संस्थान की कहानी यहीं खतम नहीं होती। बृज बिहारी के मामले व अन्य मांगों को लेकर जब कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तो ३ अक्तूबर, १९८५ को अपराह्न ४ बजे संस्थान में पुलिस आयी। पुलिस ने कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि आप लोगों को बातचीत के लिए कलक्टर और एस०पी० ने याद किया है।

संघ के अध्यक्ष डा० शशि भूषण समेत अन्य तीन पदाधिकारियों ने पुलिस की नीयत पर संदेह नहीं किया। उन्हें गांधी मैदान थाना में लगभग तीन घंटा बैठाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और हथकड़ी पहनाकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य दण्डाधिकारी ने सभी को ६ अक्तूबर को जमानत पर रिहा कर दिया। फिलहाल यह मुकदमा पटना के द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में विचाराधीन है। मुकदंमा सरकार बनाम डा० शशि भूषण प्रसाद के बीच चल रहा है। डा० शशि भूषण प्रसाद पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३, ३२३, व ३५२ के अंतर्गत अभियोग चलाया गया है। लिहाजा, कर्मचारियों में बीते वक्त के उन हादसों की कटुता अभी भी बरकरार है।

क्या बदहाली दूर कर सकेंगे?: डा० जी०पी० ओझा

पिछले आठ माह से 'अनुग्रह नारायण समाज अध्ययन संस्थान' के निदेशक का पद रिक्त है। इस पद पर किसे बैठाया जाये यह सवाल खड़ा होते ही सत्ता के शिखर पर आसीन राजनेता राजनीति शुरू कर देते हैं। 'किसे खुश किया जाये और किसे नाराज' इसी पसोपेश में यह पद रिक्त है।

निदेशक का इंतजार कर रहे इस संस्थान के पूर्वनिदेशक डा० दुर्गा नंदन सिंहा इस संस्थान से प्रस्थान करने के पूर्व इसे सर्वदा के लिए चौपट ही कर जाते। संस्थान में कार्यरत सहायक उदयकांत झा ने 'माया' को बताया, "संस्थान के लेखा विभाग के घपले को जब मैंने पकड़ा, तो मेरी प्रोन्नति रोक दी गयी और मुझे इंक्रिमेंट (वेतनवृद्धि) नहीं मिली।"

टंकक एम०जे० फिलिप, सहायक हरिश्चंद्र पाठक व अन्य कर्मचारियों को भी संस्थान के प्रबंधन से शिकायत है। विगत १९ वर्षों से कार्यरत एम०जे० फिलिप का कहना है कि सेवा में मेरे से कनिष्ठ नंदू साह को वरीय कर दिया गया। उसे प्रवर कोटि का वेतन भी मिला। बदहाली के लिए कर्मचारीगण रजिस्ट्रार महेंद्र प्रसाद पांडेय को जिम्मेदार ठहराते हैं।

गुटबंदी एवं तिकड़म में नाक तक डूबे इस संस्थान में न तो सेमिनार हो पा रहे हैं और न सही ढंग से शोध कार्य ही, पर प्रशासन बेफिक्र है।

बदहाली जगजीवन संस्थान की: "जिस संस्थान को मैंने अपना खून-पसीना एक करके सींचा है उसे अपने जीते जी बरबाद होते कैसे देख सकता हूं? लिहाजा, उम्र के इस नब्बेवें पड़ाव पर बीमार होने के बावजूद संस्थान की खुशहाली के लिए मैं वक्त-बेवक्त मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री से मिलता रहा हूं और हर बार उनसे इल्तिजा की है कि संस्थान के लिए सरकार कुछ करे," कहते-कहते संस्थान के संस्थापक व पूर्वसांसद पंडित द्वारिका नाथ तिवारी की आंखें नम हो आती हैं। पंडित तिवारी संस्थान के स्थापना-काल से लेकर इसके सरकारी अधिग्रहण तक तकरीबन नौ वर्ष संस्थान की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य व सचिव रहे, पर पूर्व के निदेशकों की मनमानी से परेशान होकर उन्होंने संस्थान आना ही छोड़ दिया।

सचमुच जिन उद्देश्यों को लेकर 'जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान' की स्थापना की गयी थी, वह बरबादी के कगार पर है। देश के कोने-कोने से आनेवाले राजनीति-शास्त्र के शोधकर्ताओं को अभी तक यहां पहुंचकर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। संस्थान की इस बदहाली के लिए वहां के कुछ पुराने मुलाजिम पूर्व के दो विद्वान निदेशकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संस्थान को 'जेबी संस्था' बना रखा था।

शोध कार्य का अर्थ विषयों की पूरी जांच-पड़ताल कर तह तक पहुंचना होता है। इससे कुछ निष्कर्षों के निकलने एवं तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त होने की आशा रहती है। सरकार विभिन्न योजनाएं और नियम बनाती है। इनके क्रियान्वयन में हजार से लेकर करोड़ों रुपए तक खर्च होता है, किंतु सही क्रियान्वयन के वास्तविक आंकड़ों का पता सरकार को प्राय: नहीं चलता। लोकतांत्रिक पद्धति में तो इन शोधों के अतिरिक्त सांसदों, विधायकों व होनेवाले सांसदों-विधायकों को संसदीय संस्कृति से अवगत कराना भी राजनीतिक शोध संस्थान का एक मुख्य कार्य है। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए १९७७ में इस संस्थान की स्थापना की गयी। पटना के 'श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल' में आयोजित एक समारोह में लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने इसका उद्घाटन किया था तथा अध्यक्षता तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने की थी। समारोह समिति ने चार लाख रुपए का प्रबंध किया था, जिसमें दो लाख, पचीस हजार रुपए स्टेट बैंक आफ इण्डिया में

फिक्स डिपोजिट में रख दिया गया जो बढ़कर अभी तक चार लाख, साठ हजार हो गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान को बिहार सरकार से एक लाख रुपए सालाना मिलते रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार अधिकांश राशि का दुरुपयोग ही होता आया है। नतीजतन, संस्थान की प्रगति आशानुकूल नहीं हो सकी।

संस्थान के प्रावधान के अनुसार मुख्य-कार्यपालक का अधिकार सचिव को दिया गया था जो मैनेजिंग कमेटी की सलाह से कार्य करते रहे। बिहार विधान सभा के स्पीकर संस्थान के अध्यक्ष हुआ करते थे। पटना के पूर्व महापौर के०एन० सहाय संस्थान के उपाध्यक्ष व स्वर्गीय सुखदेव शुक्ल तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ डा० ए०एन० उपाध्याय इसके संयुक्त सचिव थे। राम देनी राम, न्यायाधीश प्रभा शंकर मिश्र, प्रो० डा० (श्रीमती) सुखदा पांडेय, छोटेलाल सिंह, कमलदेव साह, सी०के० रोहतगी व कृष्ण बहादुर संस्थान की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हुआ करते थे

संस्थान में अब तक पांच निदेशक आये— डा० बी०बी० मिश्र (पांच माह), डा०पी०एस० पचौरी (साढ़े तीन साल), राम जनम ओझा (दो साल), डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा (एक साल छह महीना) और वर्तमान निदेशक डा० गणेश प्रसाद ओझा। इनमें डा० बी०बी० मिश्र व डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के क्रियाकलापों से सचिव संतुष्ट नहीं थे। लिहाजा, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सचिव का आरोप था कि डा० मिश्र व डा० वर्मा संस्थान के हित में कार्य नहीं करते। 'माया' से पंडित तिवारी ने बेबाक कहा, "डा० बांके बिहारी मिश्र और डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की योग्यता व विद्वता में कोई कमी नहीं है। पर अपने कार्यकाल के दौरान इन विद्वानों ने संस्थान के मूलभूत उद्देश्यों से हटकर ज्यादा रुचि अपने प्रिय विषयों में ली। चूंकि संस्थान की देखभाल हेतु सारे अधिकार मैंने डा० एस०एन० उपाध्याय को दे रखे थे, लिहाजा, डा० वर्मा मुझसे कुपित रहते थे और अंततः उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया।"

अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए डा० बी०बी० मिश्र ने 'माया' को बताया, "निदेशक होने की वजह से यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता था कि किन विषयों पर शोध होगा। विषय चुनना और उन्हें शोधकर्ताओं को देना, मेरा काम था। जब मैंने देखा कि द्वारिका नाथ तिवारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शोध-कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो मैंने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया।"

राजनीतिशास्त्र के प्रख्यात विद्वान डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा संस्थान के राजनीतिकरण से बेहद परेशान रहे। डा० वर्मा का कहना है कि पंडित द्वारिका नाथ तिवारी संस्थान को अपनी निजी संपत्ति समझते रहे। लिहाजा, संस्थान परिसर में ही उन्होंने अपना आवास भी बना लिया। धीरे-धीरे संस्थान पंडित तिवारी के लिए राजनीति करने का एक 'प्लेटफार्म' बनकर रह गया। जिन विद्वानों ने उनके सामने घुटने नहीं टेके, उन्हें इस्तीफा देकर हट जाना पड़ा। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।

संस्थान अपने दस साल की कार्यावधि में मात्र सात शोध कार्य ही पूरा कर सका है। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो उल्लेखनीय हो या जिसका कुछ व्यावहारिक महत्व हो। दुःख की बात तो यह है कि जगजीवन राम के नाम पर संस्थापित इस संस्थान में जगजीवन राम के ऊपर अब तक कोई कार्य नहीं हो सका है। संस्थान के सूत्रों के अनुसार ऐसा पूर्वसचिव और पूर्व-निदेशकों की आपसी लड़ाई के कारण हुआ है।

उपलब्धि के नाम पर तीन माह में 'डेमोक्रेसी' नामक एक पत्रिका तथा मासिक बुलेटिन प्रकाशित होती है। दस वर्ष में मात्र नौ सेमिनार संपन्न हुए। "क्या ठोस नतीजा निकला, इन सेमिनारों से। सिर्फ 'शो' है यह सब," एक शोधकर्ता कहते हैं। उन्होंने बताया, "इन नौ सेमिनारों में से अधिकांश सेमिनार ऐसे विषयों पर हुए, जिनका कि संस्थान के मूलभूत उद्देश्यों से कोई संबंध ही नहीं रहा। हां, वर्तमान निदेशक के आने के बाद से संसदीय परंपरा व विषयों से संबंधित सेमिनार होने शुरू हो गये हैं।"

अन्याय हुआ : अनुग्रह संस्थान के टंकक एम०जे०फिलिप

उल्लेखनीय है कि डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने साप्ताहिक शोध पद्धति पर एक आतंरिक सेमिनार की स्वस्थ परंपरा शुरू की थी।

इसी जद्दोजहद के बीच ग्यारह दिसम्बर, १९८६ को एक अधिसूचना जारी कर 'जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान' के अधिग्रहण को राज्यपाल पी० वेंकटसुब्बैया ने पुष्ट कर दिया। अधिग्रहण के कारणों पर प्रकाश डालते हुए सरकारी सूत्रों का कहना था कि संसदीय विधा के प्रशिक्षण एवं राजनीतिक शिक्षण संस्थान के रूप में इस संस्थान का अधिक महत्व है। साथ ही स्वर्गीय जगजीवन राम के जीवंत स्मारक के रूप में संस्थान को विकसित किया जा सकता है। संस्थान विद्वान प्रबंध समिति के हाथ में रहने के बावजूद अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका।

अधिग्रहण के बाद संस्थान के निदेशक का पद संभाला डा० गणेश प्रसाद ओझा ने जो पूर्व में पटना विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में रीडर थे। आते ही डा० ओझा ने चार खंडों में जगजीवन राम के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विचारों पर शोध शुरू करवाया है। इनकी योजना है कि ये आदिवासी क्षेत्र में उत्थान के लिए जमकर शोध परियोजनाओं को चलायेंगे और कुछेक पर इन्होंने काम काफी तेजी से करवाना प्रारंभ भी करवा दिया है। मसलन, पटना जिले के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर शोध चल रहा है तथा उन पर बहुत कुछ जमा किया जा चुका है। पटना जिले का शोध कार्य समाप्त होते ही डा० ओझा बिहार के सभी जिलों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की समस्याओं का मुआयना शोध माध्यम से कराना चाहते हैं, ताकि यह संस्थान आनेवाले नये शोधकर्ताओं के लिए आदर्श बन सके। किंतु डा० ओझा के समक्ष समस्याएं अनेक हैं। 'माया' को उन्होंने बताया, "अभी तक इस संस्थान को अपना भवन सरकार नहीं दे सकी हैं। नतीजतन,किराए के भवन में ही संस्थान चल रहा है। संस्थान को एक समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता है। वर्तमान पुस्तकालय में राजनीति, इतिहास व समाजशास्त्र की एक भी काम लायक पुस्तक नहीं है। जो भी पुस्तकें हैं, उनका 'डिस्क्रिप्टिव कैटलाग' (पुस्तक सूची) आज तक नहीं बन सका है। लिहाजा, पुस्तकालय को सही पुस्तकालय बनाने के उद्देश्य से मैंने संस्थान का 'फिक्स डिपोजिट' (सावधि जमा राशि) पुस्तकालय को देने के लिए सरकार के पास पत्र लिखा है और सरकार से इस मद के लिए अतिरिक्त सात लाख रुपए की मांग की है।"

शोध-कार्य को वृहत् रूप से चलाने के लिए वृहत् सुविधाओं की आवश्यंकता पड़ती है। किंतु शोध सहायक के नाम पर मात्र दो ही स्थायी व्यक्ति कार्यरत हैं, जबकि आवश्यकता कम-से-कम आठ की है। कुछ स्थायी शोध पर्यवेक्षक भी होने चाहिए, यहां एक भी नहीं है। अनुदान की रकम भी अभी तक काफी कम रही है। हां, वर्तमान निदेशक ने संस्थान का जो नया बजट सरकार के वित्त विभाग के पास भेजा है, उसमें अनुदान की रकम बढ़ाने की बात लिखी गयी है। इसके अतिरिक्त डा० ओझा ने सरकार के कल्याण विभाग व आई०सी०एस०आर०, दिल्ली से भी अनुदान की मांग की है। निदेशक का कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को मैंने संस्थान की सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस साल के अंत तक संस्थान को एक सही संस्थान बना दिया जायेगा। पर सवाल है कि मुख्यमंत्री के इस कोरे आश्वासन से इस संस्थान की बदहाली क्या खतम हो जायेगी? बिहार की राजधानी पटना के तीसरे और अंतिम शोध संस्थान काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान की स्थिति भी उक्त दोनों शोध संस्थानों-सी ही है। काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के सहायक निदेशक डा० चितरंजन प्रसाद सिन्हा की टिप्पणी है, "यह संस्थान नहीं रेलवे का डिब्बा है और इसका पुस्तकालय आलू का गोदाम।"

छाया : दीपक कुमार —रतीन्द्र नाथ

सत्यकथा

जनवरी १९८८
मूल्य रु० ५/-

एक अनोखी लड़की

एशियाई पिता और अंग्रेज मां की बेटी जूजू उर्फ जैनी की प्रेम-संघर्ष कथा।

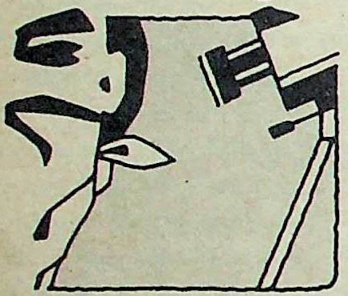

फिल्मी अंदाज में एक हत्या

बम्बई में मवालियों द्वारा जेल तोड़ कर एक माफिया सरगना की हत्या कर देने की सनसनीखेज कथा।

राजीवा का अपहरण क्यों हुआ ?

बम्बई में एक गरीब तबके के युवक द्वारा अपने आश्रयदाता की ३ वर्षीया लड़की के अपहरण की कथा। कारण जानकर आप आश्चर्य करेंगे।

डायरी ने राज खोला

मेरठ में, समाज में शराफत का मुखौटा लगाए, एक युवक की इकतरफा इश्क में उसी के दोस्तों द्वारा हत्या कर दिये जाने की कथा।

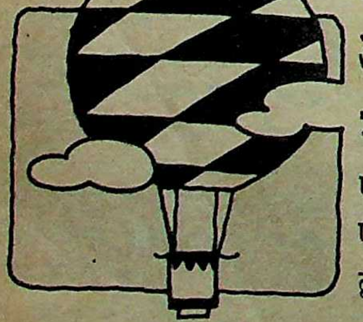

आकाश में झूलती मौत

एक ९ वर्षीय बालक के उत्सुकतावश एक गुब्बारे में बैठ जाने पर सूझबूझ द्वारा उसे बचा लिए जाने की कथा।

अन्य आकर्षण

इंसपेक्टर मुझे गोली मार दो

एक खुशहाल परिवार के युवक द्वारा उप-पत्नी के कटु व्यवहार से अपने परिवार की हत्या और खुदकशी का प्रयास करने की अछूती कथा।

कब्रिस्तान की बला

हत्याओं की सुराग में निकली पुलिस टोली में एक पुलिस अफसर के खुद अपराधी होने की नवाज खां द्वारा अन्वेषित कथा।

- विवाह का धोखा
- याददाश्त लौट आई
- दोस्त दोस्त न रहा

तथा और भी सी०आई०डी०अफसर बनकर ठगी, चोरी, शिकार, हीरो बनने की ललक आदि सशक्त कथाएं

साथ ही
सनसनी खेज सम्पूर्ण
चित्र कथा

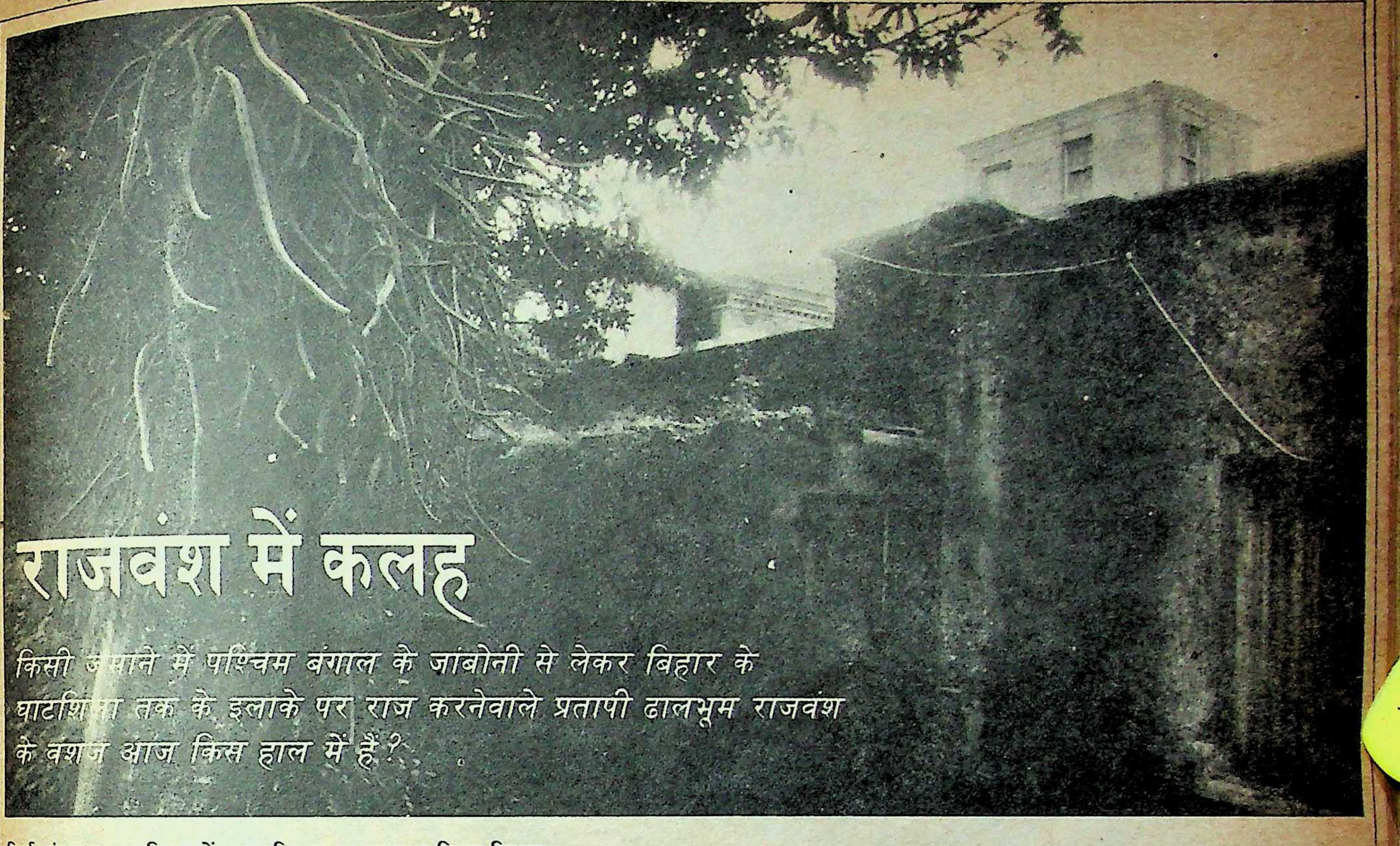

राजवंश में कलह

किसी जमाने में पश्चिम बंगाल के जांबोनी से लेकर बिहार के घाटशिला तक के इलाके पर राज करनेवाले प्रतापी ढालभूम राजवंश के वंशज आज किस हाल में हैं?

सिर्फ खंडहर : घाटशिला में राजपरिवार का राजपथ स्थित निवास

उस वीरान सड़क का नाम है—राजपथ। शायद ही कभी कोई उधर का रुख भी करता हो। इस सड़क का नाम राजपथ कोई गलत नहीं, पर इसका अभिशप्त वर्तमान किसी से छिपाये नहीं छिपता। राजपथ तो राजाओं के लिए होता है, सो पहाड़ियों से चौतरफा घिरे सिहभूम के तहत के इस कस्बानुमा शहर घाटशिला की यह सड़क भी घाटशिला के राजपरिवार के लगभग खंडहर में तब्दील हो चुके पुराने वक्त के उस विशाल भवन के पास ही पहुंचती है, जिसके अंदर रोज-ब-रोज तीव्रतर होते आंतरिक कलह और मुकदमेबाजी का माहौल गर्म है। "राजा के लड़के के पास ज़ायेंगे ? अब वहां है ही क्या, सब भाई संपत्ति की लड़ाई में जमशेदपुर से कलकत्ता तक की अदालत में मर मिटने को तैयार हैं," कहते हैं घाटशिला के एक वृद्ध व्यक्ति।

अतीत : सचमुच किसी जमाने में बंगाल के जांबोनी के इलाके से लेकर बिहार के इस घाटशिला क्षेत्र तक हुकुमत करनेवाला राजपरिवार जो ढालभूम राजवंश के रूप में विख्यात रहा आज उसकी हालत कारुणिक है। वजह वही जो आमतौर पर हर राजपरिवार के वंशजों को आज खोखला कर रही है, यानी संपत्ति की मिल्कियत को लेकर युद्ध। इतिहासकार टॉड ने अपनी पुस्तक में ढालभूम के इस राजपरिवार का विवरण देते हुए लिखा है कि ये लोग अग्निवंशी थे और इनकी आगे जाकर चार शाखाएं हुईं। पहला परमार, दूसरा परिहार, तीसरा चालुक्य या सोलंकी और चौथा चौहान। अग्निकुल की इन चार शाखाओं में परमार को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इन परमारों ने दो जगह राज्य कायम कर राजधानी बसायी। एक धार में और दूसरा मांडू में जो विंध्यगिरि के समीप था। तेरहवीं सदी के प्रथम चरण में अल्तमश ने मालवा को नैस्तनाबूत किया, तो पराजित परमार विभिन्न स्थलों पर जा बसे। इसी काल में धार नरेश के द्वितीय पुत्र जगदेव अपने सहयोगियों के संग धार से निकलकर पुरी की तरफ बढ़े और आखिरकार बढ़ते-बढ़ते वह सिहभूम के गालूडीह के समीप महुलिया पहुंचे। महुलिया के तत्कालीन शासक को जगदेव ने परास्त किया और स्वयं को उस क्षेत्र का राजा घोषित किया। यही जगदेव धवलदेब ढालभूम राजवंश के आदिपुरुष हुए। १७६७ में ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी ने ढालभूम के राजा पर चढ़ाई की। फर्गुसन ने इस राजपरिवार द्वारा शासित पश्चिम बंगाल के क्षेत्र जांबोनी से लेकर घाटशिला तक धावा किया था। आखिरकार फर्गुसन को अपनी इस मुहिम में कामयाबी मिली। पर बाद में १७७७ में जगन्नाथ धवलदेब द्वारा अंग्रेजों को नियमित रेवेन्यू देने की बात स्वीकार करने पर राजपरिवार की स्थिति संभली। इस राजवंश के २६वें उत्तराधिकारी शत्रुघ्न धवलदेब हुए, जिन्हें कोई संतान नहीं हुई। नतीजतन, उन्होंने ईश्वर चन्द्र के पुत्र जगदीश चन्द्र के नाम उत्तराधिकार की वसीयत कर दी। प्रीवी कौंसिल में भी यह मामला गया और वहां से भी जगदीश चन्द्र धवलदेब को ही ढालभूम राज का असली वारिस करार किया गया।

पुत्रों में कलह :
ढालभूम नरेश स्व० जगदीश चन्द्र धवलदेब

विवाद का कारण : जगदीश चन्द्र धवलदेब के सात पुत्र और छह पुत्रियां हुईं। पुत्रों में सबसे बड़े, नारायण चन्द्र देव धवलदेब, दूसरे, कमलेश चन्द्र, तीसरे, बिमलेश चन्द्र, चौथे, अमलेश चन्द्र, पांचवें, निर्मलेश चन्द्र, छठे, सर्जेश चन्द्र और सातवें, पंकजेश चन्द्र। फिलहाल अपने पिता के निधन के बाद से

बीमारी एक भीषण समस्या !
अस्पताली इलाज–एक मजबूरी और
महँगे खर्चे की लाचारी !

निराश न हों

हम साथ हैं सदा

अगर किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाए तो इलाज का भारी खर्च उठाने के लिए शायद आप की समस्त राशि भी पर्याप्त न हो ! सोचो कुछ और होता है कुछ।

आप सोचेगें क्या कोई रास्ता है?

जी हाँ !–आपने ओरिएण्टल इंश्योरेंस की मेडीक्लेम पॉलिसी के बारे में अवश्य सुना होगा।

मेडीक्लेम–ऐसी स्थिति से निबटने के लिए ही बनाई गई है।

थोडी सी समझदारी से भविष्य के संकट से बचा जा सकता है। इलाज कितना भी महंगा क्यों न हो जरिया निकल आता है–खास तौर से जब मेडीक्लेम आप का सहारा हो।

यह बीमा पॉलिसी खास तौर से भारी अस्पताली खर्चों से राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस की मेडीक्लेम पॉलिसी

* आयु सीमा 5 से 70 वर्ष
* लाभ तालिका के अनुसार शत प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था
* आय कर से 3000 रु. वार्षिक प्रीमियम तक कटौती की सुविधा
* पारिवारिक डिस्काउँट का प्रावधान।

लाभ तालिका

वार्षिक प्रीमियम	अस्पताल में भर्ती	घर में अस्पताली खर्च
200 रु.	10,500 रु.	3,100 रु.
250 रु.	17,600 रु.	–
350 रु.	25,500 रु.	–
600* रु.	37,750 रु.	5,250 रु.
840* रु.	52,750 रु.	7,400 रु.
1,300* रु.	82,500.रु.	11,500 रु.

* अतिरिक्त भुगतान पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है।

MED+CLAIM

ओरिएण्टल इंश्योरेंस

(भारतीय साधारण बीमा कम्पनी की सहायक क्रम्पनी)
ओरिएण्टल हाऊस, ए-25/27 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

क्योंकि आप भी नहीं जानते कब जरूरत पड़ जाये।

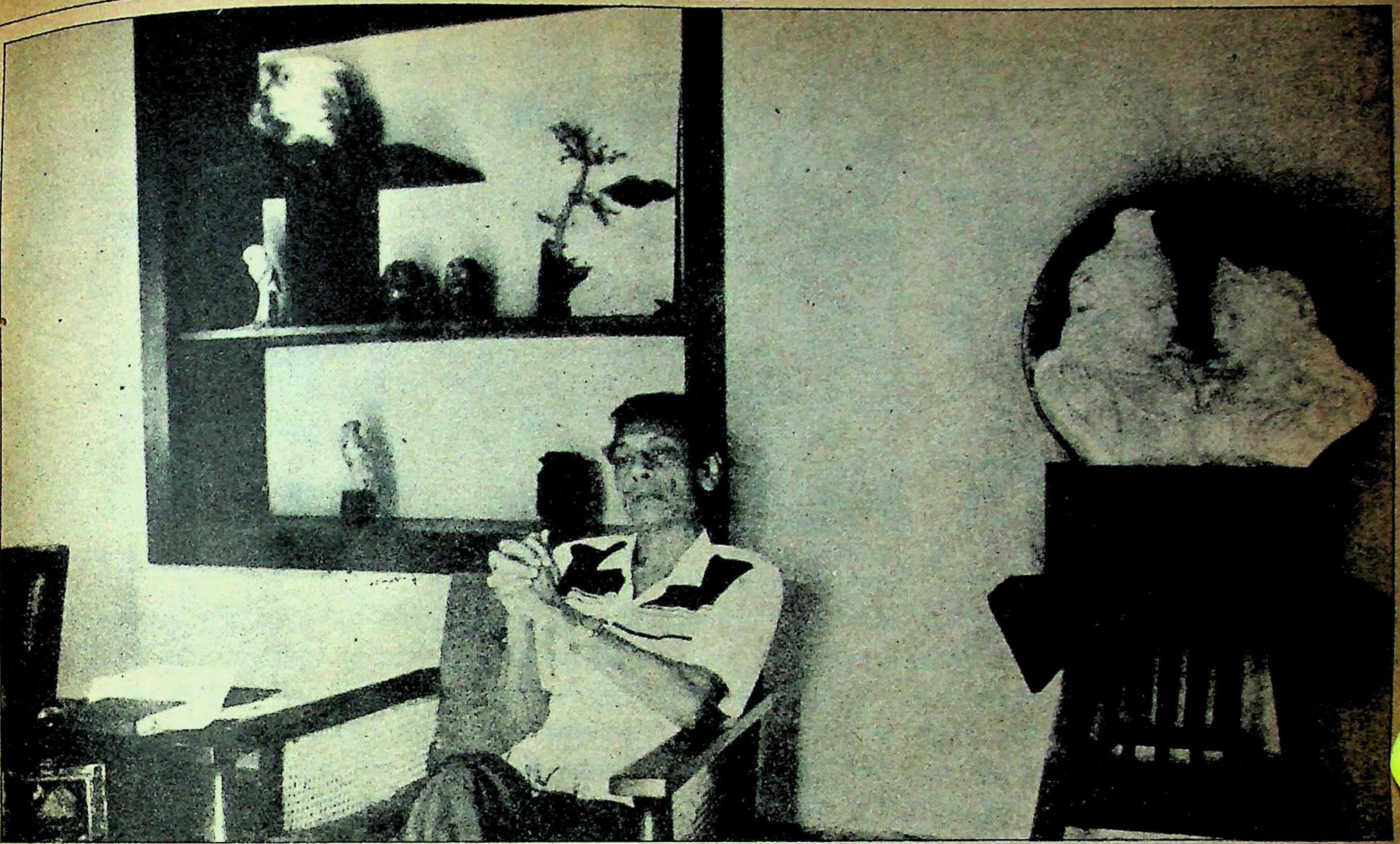

बड़े भाई ने मनमानी की : बिमलेश चन्द्र धवलदेब

ढालभूम राजपरिवार के ये सातों वारिस संपत्ति के उचित बंटवारे के लिए टकरा रहे हैं।

ढालभूम राजपरिवार में परंपरानुसार बड़े पुत्र को 'युवराज' की पदवी, दूसरे को 'हिकिम' की उपाधि, तीसरे को 'बड़ा ठाकुर' चौथे को कुंअर, पांचवें को 'मुसीब' और शेष पुत्र को 'बाबू' का खिताब दिया गया। बहरहाल, कबके खतम हो चुके राज्य के मौजूदा युवराज नारायण चन्द्र धवलदेब और बड़ा ठाकुर बिमलेश चन्द्र धवलदेब में जमकर ठनी हुई है। दूसरे भाई कमलेश चन्द्र जो 'हिकिम' थे, का निधन कुछ वर्ष पूर्व हो गया।

जमींदारी उन्मूलन के बाद संपत्ति बचाने की आपाधापी में स्व० जगदीश चन्द्र देव धवलदेब ने घाटशिला से लेकर जांबोनी तक की सैकड़ों एकड़ जमीन और मकान सहित अन्य संपत्ति अपने इन सात पुत्रों के नाम बराबर-बराबर वितरित नहीं कर शीघ्रता में किसी के नाम ज्यादा तो किसी के नाम कम जमीन व अन्य संपत्ति कर दी। उनके बड़े पुत्र नारायण चन्द्र धवलदेब पिता के निधन के बाद स्वाभाविक रूप से परंपरानुसार 'युवराज' और परिवार के अभिभावक हुए। धीरे-धीरे तनाव गहराने पर नारायण चन्द्र पर उनके अन्य भाइयों ने आरोप लगाया कि संपत्ति में उन्होंने काफी घालमेल किया है। इनकी मां तड़ित प्रभा देवी भी अभी जीवित हैं। लिहाजा, तड़ित प्रभा देवी सहित शेष पांच भाइयों ने कलकत्ता के अलीपुर लोअर कोर्ट में मामला १९८० में दायर कर दिया। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर की अदालत में नारायण चन्द्र बनाम बिमलेश चन्द्र पार्टीशन शूट चल रहा है। बड़े ठाकुर बिमलेश चन्द्र का दावा है कि घाटशिला के राजपथ रोड में स्थित पुस्तैनी मकान में वह १९६१ से ही रह रहे हैं, जबकि नारायण चन्द्र अदालत में उस पर अपना हक बताते हैं। बिमलेश चन्द्र ने डिक्ल्येरशन शूट में घाटशिला की अन्य संपत्ति पर भी दावा किया है। बिमलेश चन्द्र कहते हैं कि हम सब 'मिताक्षरा स्कूल' से संबंधित हैं, जिसके तहत पिता के निधन के बाद स्वतः सभी भाई-बहनों में संपत्ति के बराबर वितरण का प्रावधान है। पर नारायण चन्द्र ने ऐसा नहीं होने दिया। बिमलेश चन्द्र का आरोप है कि अग्रज नारायण चन्द्र ने इसके अतिरिक्त बहुत से पुश्तैनी, कीमती जेवरात भी अपने कब्जे में कर रखे हैं। बिमलेश चन्द्र के मुताबिक जांबोनी की अधिकांश संपत्ति के अतिरिक्त कलकत्ता के बालीगंज स्थित पुश्तैनी मकान पर भी युवराज नारायण चन्द्र ने कब्जा जमा रखा है।

फैसले की प्रतीक्षा : ढालभूम राजवंश के इन सात भाइयों में मात्र तीन ही विवाहित हैं, नारायण चन्द्र, बिमलेश चन्द्र और पंकजेश चन्द्र। कमलेश चन्द्र अविवाहित थे और उनका तो निधन भी हो गया और शेष तीन भी अविवाहित हैं। नारायण चन्द्र के खिलाफ बिमलेश चन्द्र की मुहिम में मां तड़ित प्रभा सहित अन्य सभी पांच भाई हैं। अदालत में संपत्ति के बंटवारे का फैसला जितना आगे खिंच रहा है, तनाव में भी इजाफा हो रहा है। बिमलेश चन्द्र हर पल सशंकित रहते हैं कि चुपचाप घाटशिला आकर उनके अग्रज नारायण चन्द्र कोई जमीन न बेच जायें। वह कहते हैं ढालभूम राजवंश के इस पुश्तैनी निवास में गुलाब का बेहद खूबसूरत उद्यान था। पर वह सब उजाड़ पड़ा है। संपत्ति को अभी संवारने से क्या लाभ? पता नहीं अदालती फ़ैसले में यह किसके हिस्से चली जाये। जाहिर है, संपत्ति के लिए सशंकित ढालभूम राजवंश के ये वारिस संपत्ति का क्षय भी हर तरह बर्दाश्त करने पर अमादा हैं।

बहरहाल, इन सब विवादों के अतिरिक्त सरकार से भी इनकी शिकायत है। बिमलेश चन्द्र कहते हैं कि संपत्ति अधिग्रहण के एवज में सरकार से हमें जो मुआवजा मिलना था, वह २० साल पहले आधा ही मिल सका। शेष राशि के लिए हम लगातार ए०डी०सी० और एल०आर०डी०सी० के पास गुहार कर रहे हैं, पर कहीं कोई सुननेवाला नहीं।

घाटशिला का अब कोई रहबर नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित यह क्षेत्र बिहार सरकार द्वारा उपेक्षित है। स्थानीय लोग कहते हैं कि घाटशिला बिहार में ही है, यह अहसास बिहार सरकार को नहीं है। हां, अगर इस राजवंश के ये मौजूदा वंशज सुदृढ़ होते, तो कुछ उम्मीद बंधती, लेकिन ये तो आपस में लड़ने में ही मशगूल हैं।

—[illegible] कुमार [illegible]

अंदर ही अंदर सुलग रहा है 'विदर्भ'

विदर्भ आंदोलन की तैयारी : (बायें से) रामरतन जानोकर, (माइक पर) रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष हरिदास आवले तथा अन्य आंदोलनकारी

महाराष्ट्र राजनीति के विशेषज्ञों का कयास है कि राजस्थान के राज्यपाल पद से त्याग पत्र देने के बाद वसंत दादा पाटील कुछ ऐसा चक्कर चलायेंगे कि मुख्यमंत्री की कुरसी पर चह्वाण की जगह दादा का कोई अपना आदमी बैठा नजर आयेगा, लेकिन विदर्भ क्षेत्र के नेताओं के बीच इन दिनों जैसी मंत्रणाएं चल रही हैं, उन्हें देखते हुए आसार किसी दूसरे प्रकार के तूफान के आने का संकेत दे रहे हैं। पिछले तीस सालों से भीतर-ही-भीतर धधक रही पृथक विदर्भ प्रांत की मांग कभी भी ज्वालामुखी-विस्फोट का रूप ले सकती है। विदर्भ के लोग महाराष्ट्र से अलग पृथक विदर्भ राज्य क्यों बनाना चाहते हैं? क्या यह आंदोलन अहिंसक रह पायेगा? :

विदर्भ के गठन को लेकर ३० साल पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह मंथर गति से ही सही, लेकिन आज भी जारी है। यह आंदोलन किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकता है, क्योंकि लोगों के मन में राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। नयी पीढ़ी में मराठा लाबी के प्रति घृणा, अविश्वास और पिछड़ेपन की कुंठा चरम शिखर पर पहुंच गयी है। सिर्फ हवा की जरूरत है और इसके लिए विदर्भ समर्थक तलवार भांजते हुए उठ खड़े हुए हैं।

महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चह्वाण ने केंद्र में जाते-जाते विदर्भ के भाग्य पर कुछ इस तरह लकीरें खींच दीं, जिसकी कसक आज भी यहां के लोगों को टीसती है। मराठा लाबी ने विदर्भ का हमेशा शोषण किया, उसे प्रगति के रास्ते से निरंतर पीछे खींचने की कोशिश की और वहां के किसी नेता को कभी भी प्रभावशाली नहीं बनने दिया, कि कहीं वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विदर्भ को महाराष्ट्र से तोड़कर अलग राज्य न बना ले। विदर्भ के साथ यह भी विडंबना रही है कि आज तक वहां ऐसा कोई नेता नहीं हुआ, जो मराठा लाबी से टक्कर लेकर उसे केंद्र और राज्य दोनों जगह पटकनी दे सके। विदर्भ के नेता भी, चाहे वे सत्तापक्ष के रहे हों या विपक्ष के, कभी एकजुट नहीं हो सके। दूसरी तरफ मामूली सी बात पर सिर फुटौव्वल पर उतारू हो जानेवाली मराठा लाबी विदर्भ के सवाल पर एकजुट हो जाती है। मुख्यमंत्री चह्वाण, वसंत दादा पाटील और शरद पवार भले ही एक दूसरे की सूरत देखना पसंद न करें, मगर विदर्भ के सवाल पर वे एक दूसरे से हाथ मिलाने में कतई नहीं हिचकिचायेंगे।

आंदोलन की पृष्ठभूमि : ३० साल पहले जब पुराने मध्यप्रांत एवं बरार राज्य को विभाजित करके मध्य प्रदेश तथा बंबई द्विभाषी राज्य की स्थापना की गयी, तभी विदर्भ अंचल के लोगों ने बंबई राज्य (अब महाराष्ट्र) में शामिल होने का विरोध किया था। उन्हें ज्यादा नाराजगी इस बात पर थी कि न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के पृथक विदर्भ राज्य बनाने की मांग को जायज मानने के बावजूद केंद्र सरकार ने जबरदस्ती विलय का फैसला किया।

महाराष्ट्र आंदोलन के चलते विदर्भ में अलग राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। बंबई तथा पश्चिमी महाराष्ट्र के नेता मराठी भाषियों के लिए अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे, जबकि उनका नागपुर या विदर्भ के दूसरे शहरों में कोई प्रभाव नहीं था। महाराष्ट्र स्थापना का आंदोलन लगभग गैर राजनीतिक तथा सर्वदलीय बन गया। श्रीपाद अमृतडांगे (कम्युनिस्ट) से लेकर एस०एम० जोशी (समाजवादी) इस आंदोलन के अगुवा थे। विरोध था, तो सिर्फ कांग्रेस का।

चुनाव हुए। पश्चिमी महाराष्ट्र में यशवंत राव चह्वाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस का संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समिति के उम्मीदवारों ने भट्ठा बिठा दिया। सिर्फ विदर्भ में कांग्रेस की भारी जीत हुई। विदर्भ की बदौलत ही श्री चह्वाण तब मुख्यमंत्री बन सके, परंतु जब विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग उठी, तो सेठजी और भट्टजी (ब्राह्मण) का आंदोलन कहकर तिरस्कार किया गया।

राज्य और केंद्र की अनदेखी से पृथक विदर्भ आंदोलन धीरे-धीरे उग्र होता चला गया। अकसर हिंसक घटनाएं भी होने लगीं। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोलीचालन की नौबत भी कई मर्तबा आयी।

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के नेता श्रीपाद महादेव (एस०एम०) जोशी तथा मुख्यमंत्री यशवंत राव चह्वाण के सामने विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें लाठी चार्ज तक करना पड़ा। १५ दिसंबर, १९५९ को ब्रजलाल बियाणी संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने २६ जनवरी, १९६० से अकोला, अमरावती, वर्धा आदि जिलों की पदयात्रा की, सत्याग्रह शुरू किया, परतु हिंसा भड़कने पर ४ मार्च को आंदोलन स्थगित कर दिया।

२५ अप्रैल से विरोध सप्ताह शुरू हुआ जिसने हिंसक रूप ले लिया। १ मई, १९६० को टी०जी० देशमुख आदि ने विरोध दिन मनाने का आह्वान किया। हिंसा की वारदातों के कारण धारा १४४ तथा कर्फ्यू लगाया गया। हमलावरों ने एक पुलिस चौकी और एक थाने को आग लगाने की कोशिश की। १३ मई तक कर्फ्यू लागू रहा और इस दौरान कुल ६ लाख रुपए की संपत्ति नष्ट हुई, १२५३ व्यक्ति हिरासत में लिये गये।

साक्षात्कार/नासिक राव तिरपुड़े

विदर्भ को अलग राज्य बनाना होगा

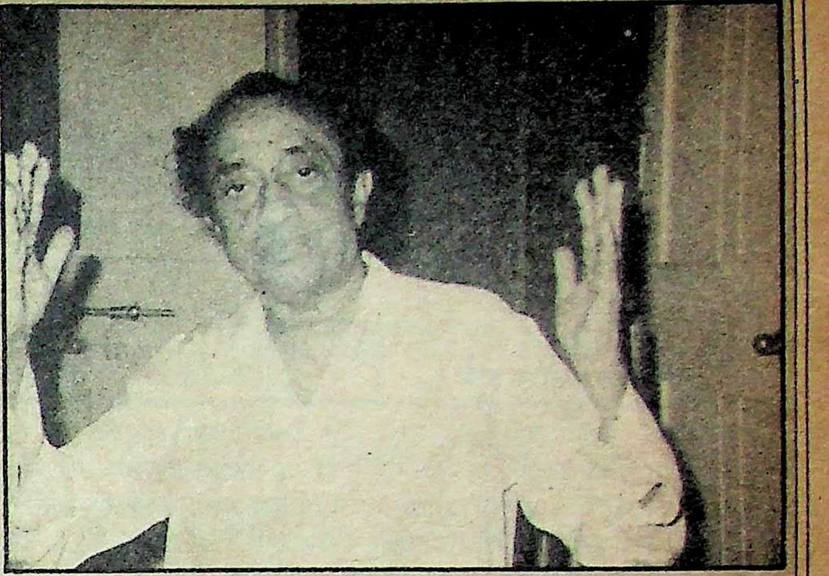

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री नासिक राव तिरपुड़े विदर्भ के उन बेबाक तथा मुंहफट नेताओं में से हैं, जिन्होंने अपनी जिद के कारण अनेक मुसीबतें झेलीं। १९७८ में मंत्री-पद छोड़कर वह महाराष्ट्र में इंदिरा कांग्रेस के पहले संस्थापक बने। यशवंत राव चह्वाण, वसंत दादा पाटील, शरद पवार तथा केंद्र में बैठी जनता पार्टी का मुकाबला करते हुए इंदिरा कांग्रेस को ७२ (कांग्रेस-स को ७१ सीटें मिलीं) सीटें दिलाने में सफल हुए। इन ७२ विधायकों में से ५६ विदर्भ के थे। वह एक कुशल प्रशासक, घाघ राजनीतिज्ञ तथा मराठा लाबी के विरोधी एवं विकल्प के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत हैं, 'माया' से उनकी लंबी बातचीत के कुछ अंश:

माया: आपने पृथक विदर्भ की मांग क्यों उठायी?

तिरपुड़े: निजी स्वार्थ पूरा करने में जुटे नेता इस बात का ध्यान नहीं रखते कि विदर्भ अपनी खुशी से महाराष्ट्र में नहीं मिला। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग राज्य दिया, परंतु कांग्रेस नेतृत्व के आदेश पर १९५६ में विदर्भ ने बंबई द्विभाषी राज्य में जाना मंजूर कर लिया। द्विभाषी राज्य द्वारा तब यदि विदर्भ अलग राज्य बन जाता, तो १९६० में यशवंत राव चह्वाण मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। विदर्भ ने दोबारा त्याग किया। यशवंत राव ने विदर्भ के विकास के वायदे किये, परंतु आज तक उनका पालन नहीं हुआ। ५ साल पहले मैंने विदर्भ विकास महासभा बनायी। तब मैंने कहा था कि हम अलग नहीं होना चाहते, परंतु पश्चिमी महाराष्ट्र का नेतृत्व विदर्भ के विकास पर ध्यान दे। मैंने सरकार से विदर्भ को जांचने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति की मांग की। उन्होंने दांडेकर समिति बनायी, परंतु उसकी रपट से हम संतुष्ट नहीं हैं। रपट पर अमल भी नहीं हुआ। इन सब कारणों से पिछले वर्ष मैंने अलग विदर्भ राज्य की मांग उठायी।

माया: इसके लिए आंदोलन करेंगे या मांग करने से राज्य मिल जायेगा?

तिरपुड़े: स्वतंत्र विदर्भ के लिए सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक जनमत तैयार करेंगे। अब दो ही रास्ते हैं। या तो जिस क्षेत्र (पश्चिमी महाराष्ट्र) ने ज्यादा खर्च किया, उसे धन देना बंद करके विदर्भ पर खर्च किया जाये या फिर विकास की वर्तमान पद्धति जारी रहे, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक शक्ति वाला जीतेगा। दूसरे रास्ते से कांग्रेस का वर्चस्व जाता रहेगा। यदि कांग्रेस का राज्य कायम रखना है और विकास भी करना है, तो विदर्भ को अलग राज्य बनाना होगा।

> *१९५६ में विदर्भ ने बंबई द्विभाषी राज्य में जाना मंजूर कर लिया। द्विभाषी राज्य द्वारा तब यदि विदर्भ अलग राज्य बन जाता, तो १९६० में यशवंत राव चह्वाण मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। विदर्भ ने दोबारा त्याग किया। यशवंत राव ने विदर्भ के विकास के वायदे किये, परंतु आज तक उनका पालन नहीं हुआ।*

माया: इतना आसान तो नहीं है पश्चिमी महाराष्ट्र के नेताओं को मनाना?

तिरपुड़े: मैंने अनेक नेताओं तथा विधायकों से बात की है और इससे मेरा उत्साह बढ़ा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के नेता भी यह सोचने लगे हैं कि जबर्दस्ती ज्यादा दिन तक विदर्भ को बांधे नहीं रखा जा सकता।

माया: इस आशावादिता का आधार?

तिरपुड़े: यदि विकास का फिर वायदा करते हैं, तो बकाया चुकाने के लिए ६००० करोड़ रुपए कहां से लायेंगे। कांग्रेस का आधार मजबूत करने के लिए भी विभाजन लाभदायी है, वरना संतुलन बिगड़ने से संगठन कमजोर होगा।

माया: कुछ लोग चाहते हैं कि विदर्भ के लिए विकास बोर्ड बने ताकि बिना अलग राज्य बनाये विकास हो?

तिरपुड़े: मेरी राय अलग है। कांग्रेस में फिजूल झगड़े बढ़ेंगे। योजना तथा खर्च के आंकड़ों को लेकर सरकार में मतभेद होंगे तथा विकास बोर्ड की स्वायत्तता को लेकर राज्यपाल-मुख्यमंत्री-मंत्री-विधानसभा के बीच कटुता तथा अविश्वास पैदा होगा। पहले कई बार प्रयोग किये जा चुके हैं। फिर एक बार प्रयोग में हारकर १० साल बाद विदर्भ की मांग उठाना, समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं।

माया: इतने दिन तक विदर्भ के नेता बड़े पदों पर रहे। ११ साल वसंत राव नाईक मुख्यमंत्री रहे, आप, नरेंद्र तिड़के, शेषराव वानखेड़े सालों तक मंत्री थे। यह मांग तब क्यों नहीं उठायी?

तिरपुड़े: शादी के तत्काल बाद झगड़ा या अन्याय हो, तो तलाक नहीं मांगा जाता। फिर यह तो राज्य का मामला है। पहले १० वर्ष तक महाराष्ट्र की राजनीति में पश्चिमी महाराष्ट्र (मराठवाड़ा) और विदर्भ या मराठा और गैर मराठा के बीच संतुलन रखने की कोशिश की जाती थी। आज वह संतुलन नहीं है। अंतुले के बाद गैर निष्ठावानों के हाथ में पूरा राज आ गया। विदर्भ से १९७८ में चुनकर आये ५६ विधायकों में से आज सिर्फ ५ विधायक हैं। बाकी के टिकट काट दिये गये।

माया: क्या अलग राज्य की मांग पार्टी अनुशासन के खिलाफ नहीं है?

तिरपुड़े: कतई नहीं। मैं तो पार्टी में संतुलन बनाये रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहीं भी पार्टी नियमों की मर्यादा भंग की होती, तो मुझसे जवाब-तलब किया जाता।

माया: क्या आपको दो मराठी भाषी राज्य बनना ठीक लगता है?

तिरपुड़े: दो तो हो ही गये। गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया। हिंदी तथा बंगला भाषी राज्य एक से ज्यादा हैं। केरल, बंगाल, हरियाणा से विदर्भ बड़ा है। यहां कोयला, पानी, खनिज सभी प्रचुर मात्रा में हैं। इसलिए वह आत्मनिर्भर राज्य होगा तथा तेजी से तरक्की करेगा। **—बंबई ब्यूरो**

समर्थन: श्रीधर राव वासुदेव धाबे

> *सारा गुबार अंदर-ही-अंदर उबल रहा है और एक दिन विदर्भ की मांग फिर सड़कों पर आयेगी।*

कांग्रेसी नेताओं ने ३०-३१ मार्च, १९६१ को यशवंत राव चह्वाण का जन्मदिन मनाने का ऐलान किया, जिसके विरुद्ध आंदोलनकारियों ने पुतले जलाने की धमकी दी। पुलिस को प्रतिबंधक आदेश जारी करने पड़े। इसके बावजूद वी०एस० पांडेकर की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसमें यशवंत राव की तस्वीरें फाड़ कर फेंकी गयीं। एक गोदाम पर हमला करनेवाली भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलायी। दो व्यक्तियों को गोली लगी। उसी दिन दूसरी भीड़ ने इतवारी थाना जलाना चाहा और वहां भी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसी तरह कृषि विद्यापीठ आंदोलन में नौ लोगों की जानें गयीं। ५ से ७ सितंबर (१९७१) के बीच पुलिस गोली चालन से करीब एक दर्जन लोग मरे थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी०जी० गटणे के जांच आयोग ने जांच की थी। उस वक्त सरकार की ओर से विदर्भ आंदोलन पर ब्यौरा तैयार किया गया, मगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

एकतरफा विकास: महाराष्ट्र राज्य स्थापना के २५ साल बीत-जाने के बाद भी विदर्भ की मांग में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो कांग्रेस के नेता भी इसकी वकालत खुलकर करने लगे हैं। ३० साल पुराने असंतोष, रोष तथा आंदोलन की जड़ें गहरी होने का बड़ा कारण यही है कि तरक्की की एकतरफा दौड़ जारी रही। पश्चिमी महाराष्ट्र के जल-हीन पठार में गन्ने तथा अंगूर लहलहाने लगे। गांव-गांव तक बिजली और सड़क पहुंच गयी। सहकारी संस्थाओं की जड़ें इतनी मजबूत हो गयीं कि उनके बूते प्रदेश तथा देश की राजनीति चलने लगी। तीन हजार की आबादी वाले गांव में भी इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेज खुलने लगे।

उधर विदर्भ में नदियां तथा भूतलीय जल-स्रोत बेकार जाते रहे, न सिचाई योजनाएं बनीं और न पूरी हुईं, न कर्ज, अशिक्षा तथा रूढ़ियों से टूटते गांव के गरीब को कोई दिलासा ही मिली। पिछले २०-२५ सालों में विदर्भ में अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन हुए, परंतु हर सफल आंदोलन के बाद उसका नेता अपनी कीमत वसूलते हुए कांग्रेस में जा मिला। आंदोलन के आदि नेता बापूजी अणे को विदर्भ के लोगों ने सर आंखों पर लिया। उन्हें लोकनायक की पदवी मिली। श्री अणे ने अलग राज्य की वकालत करते हुए कहा था, "भाषा (मराठी) की भावुकता में विदर्भ आंदोलन के विरोधी यह नहीं सोच रहे कि जब महाराष्ट्र के बहुमत के कब्जे में विदर्भ जायेगा तब हजारों युवकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। विदर्भ की कुल पूंजी लूट ली जायेगी और उसके हाथ में होगा-खाली (भिक्षा) पात्र।"

लोकनायक को विदर्भ ने जिताकर लोकसभा में भिजवा दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने आंदोलन ध्वस्त करने के लिए बापूजी को तोड़ा और उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया।

विदर्भ के एक और नेता जाम्बवंत राव धोते महाराष्ट्र और देश की राजनीति में चर्चित रह चुके हैं। यवतमाल की जनता ने, जब वह जेल में थे, चुनकर विधानसभा में भिजवाया, जहां उन्होंने विदर्भ के नाम पर पेपरवेट फेंका। फिर भी लोगों ने उन्हें लोकसभा के लिए जिताया। आपातकाल में चुप्पी साधे बैठे जाम्बवंत राव १९७७ में जगजीवन राव की पार्टी की ओर से चुनाव लड़े और हार गये। अगले ही साल उन्होंने इंदिरा गांधी का दामन थाम लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें महाराष्ट्र का प्रति मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। अब वह भी किनारा किये हुए हैं। विदर्भ आंदोलन के दिमाग त्रिंबकराव उर्फ टी०जी० देशमुख की सधी कलम तथा वाक्चातुरी ने आंदोलन को युवकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। तब दिल्ली बुलाकर सत्तर के दशक में श्रीमती गांधी ने उनके सामने राज्यसभा सदस्य बनने का प्रस्ताव रखा। बाद में वह महाराष्ट्र में मंत्री रहे। आजकल वसंत दादा पाटील के इर्द-गिर्द दिखते हैं, परंतु आंदोलन के बजाय विदर्भ-चर्चा तक सीमित हैं।

विदर्भ की सीढ़ी चढ़कर सत्ता की कुरसी छूने वाले छुटभैये नेताओं की लंबी फेहरिस्त है – वालकृष्ण वासनिक, जो संभवत: पिछले दशक में सबसे कम आयु के सांसद थे, महाराष्ट्र के कृषि और श्रममंत्री भगवंत राव गायकवाड़, भूतपूर्व सांसद राम हेडाऊ, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री नानाभाऊ अम्बेडकर, विधायक-पिता राजे विश्वेश्वर राव आदि।

राजनीतिज्ञों के कुरसी-प्रेम ने आंदोलन को अस्थायी झटके दिये, परंतु पिछड़ापन दूर नहीं होने तथा दूसरे अंचलों की तेज-रफ्तार तरक्की ने उनकी आंखें खोल दीं। एक बार फिर पृथक विदर्भ की मांग उठने लगी। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र के भूतपूर्व उपमुख्यमंत्री नासिक राव तिरपुड़े ने पहली बार

साक्षात्कार/**रामरतन जानोकर**

विकास बोर्ड से कुछ नहीं होगा

रामरतन जानोकर नागपुर के महापौर रह चुके हैं। पृथक विदर्भ आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आंदोलन के एक चर्चित नेता स्व० आवले बाबू के वह अभिन्न साथी थे। प्रस्तुत हैं, 'माया' की उनके साथ हुई बातचीत के कुछ अंश:

माया: पश्चिमी महाराष्ट्र के नेताओं को खुश रखने के लिए केंद्र सरकार ने विदर्भ आंदोलन की हमेशा अनदेखी की है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?

जानोकर: फजल अली कमीशन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी एक कमीशन बैठाया था और उसने भी पृथक विदर्भ राज्य बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार विदर्भ के बलबूते पर ही बनती है। इसलिए केन्द्र विदर्भ को अलग करके महाराष्ट्र में कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। नेहरू ने यही सोचकर यह मांग नहीं स्वीकार की थी और आज भी यही हो रहा है।

माया: यदि विदर्भ आंदोलन के नेता उस समय पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर अड़े रहते, तो शायद वे सफल हो जाते।

जानोकर: हां, उस समय यह असंभव नहीं दिख रहा था।

माया: आज पहले जैसे नेता नहीं हैं और आंदोलन भी दम तोड़ रहा है। आपको क्या लगता है?

जानोकर: यह सही है कि मौजूदा नेतृत्व पर जनता का विश्वास उतना नहीं है जितना पहले होता था। इसका कारण है कई नेताओं द्वारा स्वार्थवश आंदोलन को अधर में छोड़कर चले जाना। लेकिन जनता अभी भी पृथक विदर्भ चाहती है।

माया: कुछ लोग पृथक विदर्भ की जगह विकास बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। आप इस मांग से कितना सहमत हैं?

जानोकर: विकास बोर्ड से किसी का भला नहीं होगा। पृथक विदर्भ ही विदर्भ को विकास पथ पर अग्रसर कर सकता है। बोर्ड कागजों पर कार्यवाही करते हैं। राजनीति में लिखित करारों का उतना महत्व नहीं होता और न ही उसे कोई मानता है। 'नागपुर करार' इसका उदाहरण है।

—शेषराव मेश्राम

मांग की कि पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं को चाहिए कि वे विदर्भ को अलग राज्य बनाने में मदद करें, ताकि दोनों जगह कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार रहे। विपक्ष में रहकर गलतियों की माफी मांगते हुए पिछले दिनों जाम्बवंत राव धोते ने भी एक सम्मेलन बुलाया।

इन नेताओं का कहना है कि विदर्भ तथा बंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच विकास की खाई कांफी बढ़ गयी है और उसे भरना संभव नहीं है। बढ़ती मांग से सावधान होकर महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के अर्थशास्त्री डा० वि०म० दांडेकर की अध्यक्षता में समिति बनायी। पिछली बकाया राशि को लेकर मतभेद थे। विदर्भ के नेताओं का आरोप था कि सही आकलन नहीं किया गया। सरकार ने रपट पर विचार करने के लिए अधिकारियों की समिति बना दी, जोकि अब तक विचार ही कर रही है।

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद-३७१ का सहारा लिया। विदर्भ महाराष्ट्र (तब बंबई) में मिलाते समय (२८ सितंबर, १९५३) 'नागपुर करार' किया गया, जिसमें मराठीभाषियों का एक राज्य बनाते समय निम्नलिखित वायदे किये गये :

नये राज्य में राजधानी नहीं रहने पर भी नागपुर का महत्व कम नहीं होने दिया जायेगा।

विदर्भ की आबादी के अनुपात से वित्तीय प्रावधान किया जायेगा तथा खर्च होगा। हर साल इसका विवरण विधानसभा में पेश किया जायेगा।

पदों तथा नौकरियों में आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों तथा संस्थाओं में समान वितरण किया जायेगा।

नागपुर में बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ रहेगी तथा साल में एक बार निश्चित अवधि के लिए विधानसभा का अधिवेशन नागपुर में होगा।

अनुच्छेद-३७ में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया कि वह विदर्भ मराठवाड़ा (महाराष्ट्र), तथा कच्छ (गुजरात) के लिए अलग विकास बोर्ड बनायें। इस तरह बनाये गये बोर्ड की कामकाज-रपट हर साल राज्य विधानसभा के सामने रखी जाये।

विदर्भ का पिछड़ापन दूर करने के हिमायती नेताओं के दो धड़े हो गये हैं। महाराष्ट्र के भूतपूर्व उपमुख्यमंत्री नासिक राव तिरपुड़े यह मानते हैं कि विकास बोर्ड से पिछड़ापन दूर नहीं होगा तथा अलग राज्य बनना चाहिए। महाराष्ट्र के सर्वाधिक सम्मानित नेता एस०एम० जोशी ने भी कहा कि यदि विदर्भ का पिछड़ापन दूर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उसे अलग राज्य बनाना बेहतर है। जाम्बवंत राव धोते खोयी प्रतिष्ठा जुटाते हुए फिर अलग राज्य का आंदोलन छेड़ने के पक्षधर हैं।

उधर विदर्भ विकास मंडल संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीधर राव वासुदेव धाबे विकास बोर्ड के हिमायती हैं। १९८२ में उन्होंने विकास बोर्ड बनाने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। १९८५ में महाराष्ट्र विधानसभा ने, नोक-झोंक तथा तनाव के वातावरण में सर्वसम्मति से विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। केंद्रीय गृहमंत्री ने प्रस्ताव में कुछ खामियां पायीं और कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटील निलंगेकर केंद्र को सफाई पेश करते, तब तक उनकी सरकार चली गयी। नये मुख्यमंत्री शंकरराव चह्वाण ने विकास बोर्ड बनाने का विरोध किया। उन्होंने 'माया' से बातचीत में कहा कि विदर्भ के विकास के लिए उनके पास वैकल्पिक प्रस्ताव हैं। यदि सभी वर्गों के लोग तैयार हो जायें, तो वह इसे सदन में लाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री का विरोध देखकर विकास बोर्ड की मांग करनेवाले अधिकांश नेता दुम दबाकर बैठ गये हैं। केंद्रीय मंत्री वसंत साठे जरूर बोर्ड की मांग के पक्षधर हैं, परंतु इसके पीछे उनका असली स्वार्थ मुख्यमंत्री चह्वाण की इमेज खराब करना है, जिन्हें वह कतई पसंद नहीं करते। लोकसभा सदस्य बनवारी लाल पुरोहित ने इस मामले को प्रधानमंत्री के सामने रखा तथा बोर्ड बनाने का अनुरोध किया।

आम आदमी यह मानकर चलता है कि विदर्भ के लिए गंभीरता से सोचने वाले नेतृत्व का अभाव है। इसीलिए सारा गुबार अंदर-ही-अंदर उबल रहा है और एक दिन विदर्भ की मांग फिर सड़कों पर आयेगी।

—बंबई ब्यूरो

मनोरमा

१५, दिसम्बर १९८७

बुनाई
विशेषांक

बुनाई के बेहतरीन, एकदम नये १५ नमूने
सारे परिवार के लिए

आवरण कथा

इतवार को झगड़ा सोमवार को प्यार,
पति-पत्नी का यह कैसा व्यवहार ?

पति-पत्नी में आज झगड़ा तो कल प्यार
—यह एक बहुत सामान्य सी चीज है,
पर यही झगड़ा अगर जल्दी ही सुलह
में न बदले तो मुश्किलें भी
खड़ी हो जाती हैं। पति-पत्नी को इन
झगड़ों के संबंध में कैसा दृष्टिकोण रखना
चाहिए ?
पति-पत्नी के सम्बन्धों पर एक रोचक
विचारपूर्ण रचना।

अन्य आकर्षण

मेरी सुहागरात : 'उस रात पतिदेव घर ही नहीं आये'
व्यंजन : सरदी के सदाबहार व्यंजन
सौन्दर्य : आपके सौन्दर्य को निखारे-फेसमास्क
दस्तकारी : घर पर ही बनाइये ग्रीटिंग कार्ड्स

दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक प्रकाश्य

मूल्य : ६.००

सौतेला व्यवहार

महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा लाबी का वर्चस्व होने के कारण विदर्भ हमेशा पक्षपात का शिकार होता रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जहां कदम-कदम पर कारखाने लगे, छोटे-छोटे गांवों में बिजली पहुंची और सिंचाई के साधन उपलब्ध होने लगे, वहीं विदर्भ की अनदेखी होती रही। पिछले तीस वर्षों में विदर्भ की नाममात्र को प्रगति हुई है।

चीनी कारखाने: पश्चिमी महाराष्ट्र की तरक्की के स्रोत हैं- चीनी कारखाने। हर संभव तरीके से पानी उपलब्ध कराकर गंन्ने की खेती को प्रोत्साहन दिया गया और शक्कर के सहकारी कारखांने चालू किये गये। बाद में उन्हें अल्कोहल तथा शराब बनाने की इजाजत भी दे दी गयी, जिसके कारण कारखाने के मालिक रातोरात लखपति-करोड़पति हो गये।

१० साल पहले १९७८ में महाराष्ट्र सरकार ने ३० किलोमीटर के दायरे में दूसरा चीनी कारखाना खोलने पर रोक लगायी थी। उद्देश्य यह था कि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कारखाने खुलें, मगर इस नियम की खुलकर अवहेलना हुई तथा एक-एक जिले में १०-१० चीनी कारखाने खुल गये। १९८४ में श्रीमती गांधी ने शक्कर नीति बदलकर पश्चिमी महाराष्ट्र में नये चीनी कारखाने खोलने पर रोक लगा दी। उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र को एक, विदर्भ को पांच तथा मराठवाड़ा को चार लाइसेंस दिये। इसके विरुद्ध यशवंत राव चह्वाण प्रतिनिधिमंडल लेकर गये थे।

१९८६ में ५६ प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजे गये, जिनमें से ३२ पश्चिमी महाराष्ट्र के हैं। विदर्भ के १०, मराठवाड़ा के १२ तथा कोंकण के दो प्रस्ताव हैं। यदि राज्य सरकार ईमानदार होती, तो पश्चिमी महाराष्ट्र का एक भी प्रस्ताव न भेजती। राज्य के १०० कारखानों में से ३२ चीनी कारखाने बीमार हैं और बंद हैं। ये सभी पश्चिमी महाराष्ट्र के हैं, जबकि विदर्भ में गन्ना तथा उसका रस दोनों अच्छी गुणवत्ता के हैं।

उद्योग: महाराष्ट्र सरकार के १९८७ के आंकड़ों के अनुसार विदर्भ में नागपुर को छोड़कर बाकी सब जिलों में उद्योग का प्रतिशत एक से भी कम है। ९० प्रतिशत कारखाने कच्चे माल के अभाव, सरकारी सहायता, कर्ज मिलने में दिक्कत या अन्य कारणों से बंद हैं। राज्य का ६० प्रतिशत कपास विदर्भ के पांच जिलों में होता है, परंतु वहां कपड़ा मिल या सूत-कताई मिलें नहीं खोली जातीं। हचलकरंजी (जिला-कोल्हापुर) में सालाना सिर्फ ८० क्विंटल कपास पैदा होता है, मगर फिर भी एशिया की सबसे बड़ी सूत-कताई मिल वहां है। इसके लिए कपास दूसरे स्थानों से मंगाया जाता है।

सिंचाई: विदर्भ में पानी की सुविधा होते हुए भी सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं होतीं। नया राज्य बनने के बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के छोटे-छोटे नालों पर बांध बन गये, परंतु विदर्भ अंचल में बड़े बांध की योजना १० साल या ज्यादा समय से अटकी पड़ी है।

कुल २५ बड़ी और ४८ मझोली सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन हैं। इनमें से १३ बड़ी तथा १६ मध्यम दर्जे की योजनाएं विदर्भ की हैं। अप्रैल, १९८६ तक महाराष्ट्र सरकार ने २ बड़ी तथा ११ मध्यम दर्जे की योजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दी, जिनमें से विदर्भ के लिए एक भी बड़ी योजना शामिल नहीं की गयी।

पूरे महाराष्ट्र का ७० प्रतिशत वन विदर्भ में है, परंतु मुख्य वन संरक्षक का मुख्यालय पुणे में है। दस वर्ष की कोशिशों के बाद सरकार ने मंजूर किया कि इसे नागपुर भेजा जाये, परंतु पुणे के कर्मचारियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया।

> करीब १७ साल संसद सदस्य और ७ साल से केन्द्रीय मंत्री वसंत साठे अमरावती-नरखेड़ रेल लाइन या अमरावती को मुख्य लाइन पर लाने के लिए कुछ न कर सके। १९८४ में पी०वी० नरसिंहराव सुरक्षित चुनाव क्षेत्र की तलाश में रामटेक आये। उन्होंने फिर एक बार रेल लाइन की बात उठायी, परन्तु स्थिति वही ढाक के तीन पात रही।

केन्द्रीय मंत्री वसंत साठे जब उपचुनाव में लोकसभा के लिए चुनकर आये, तो उन्होंने पहली बार घोषणा की कि अमरावती को मुख्य रेल लाइन से जोड़ा जायेगा। अमरावती से १५ किलोमीटर दूर बडनेरा जंक्शन है। बंबई-कलकत्ता लाइन पर यह बड़ा स्टेशन है। ३० साल पहले बडनेरा अमरावती-नरखेड़-इटारसी रेल लाइन का सर्वेक्षण हुआ था। यदि इसे बनाया जाता, तो कपास और संतरे की फसल को काफी लाभ होता। करीब १७ साल संसद सदस्य और ७ साल से केन्द्रीय मंत्री वसंत साठे अमरावती नरखेड़ रेल लाइन या अमरावती को मुख्य लाइन पर लाने के लिए कुछ न कर सके। १९८४ में पी०वी० नरसिंहराव सुरक्षित चुनाव क्षेत्र की तलाश में रामटेक आये। उन्होंने फिर एक बार रेल लाइन की बात उठायी, परंतु स्थिति वही ढाक के तीन पात रही।

हर क्षेत्र में यही हाल है। नतीजा यह हुआ है कि ग्रामीण किसान कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। कृषि में स्नातक होकर गांव लौटे किसान-पुत्र सौतेले बर्ताव से क्षुब्ध होकर शेतकारी-संघटन में शामिल हो गये हैं। उन्होंने भू-राजस्व (लगान) तथा अन्य कर्ज की वसूली करने आने वाले अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अनेक गांवों में मंत्रियों के कार्यक्रम नहीं होने दिये जाते। अगर वे आ ही गये, तो किसान नारे लगाकर कार्यक्रम ध्वस्त कर देते हैं।

दूसरी ओर सट्टा, वेश्यावृत्ति, अवैध शराब बनाने जैसे अपराध विदर्भ के गांवों में बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी कमाई का इससे आसान जरिया दूसरा नहीं हो सकता। किसान नेता तथा एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर शरद पाटील ने तो यहां तक बताया कि कुछ गांवों के पटेल (पुराने जमींदार) ही आजकल दूसरों के नाम से सट्टे का धंधा करते हैं।

पूरे देश में विदर्भ के जिलों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। यवतमाल जिले में ५३ प्रतिशत, अमरावती में ५२ प्रतिशत, बुलढाणा में ४४ प्रतिशत, वर्धा में ४८ प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। इससे गरीबी का पता लगता है। सड़कों के बारे में भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार की दांडेकर समिति ने विदर्भ में ९५० करोड़ रुपए विकास पर खर्च करने को कहा था, जो नहीं हुआ।

पिछड़ेपन के प्रतिकार के लिए पहली बार विदर्भ के मतदाता ने १९८५ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी गढ़ तोड़ा तथा विपक्ष को करीब आधी सीटें जीतने में मदद की। शरद पवार के दलबदल के बाद विधानसभा में भले स्थिति बदली हो, गांव का किसान अभी भी नाराज है। इसलिए विदर्भ के लिए विकास बोर्ड या नये राज्य की मांग होती रहेगी।

—बंबई ब्यूरो

साठ साल के बूढ़े या साठ साल के जवान?

कभी आपने ग़ौर किया है कि सड़क पर दौड़ते यह बुज़ुर्ग ६० बरस की उम्र में भी क्यों शक्ति और स्फूर्ति से भरपूर हैं? जबकि आप अभी ३० ही के हैं फिर भी थके-थके से रहते हैं.

इसका जवाब है, केसरी जीवन.
हर दिन, दिन में दो बार दो छोटे चम्मच.

ज़ाफ़रान (केसर)–अनमोल तत्त्व!
केसरी जीवन की बोतल खोलिए. ज़ाफ़रान की लुभावनी खुशबुएँ सबसे पहले आपका स्वागत करेंगी. शुद्ध, असली ज़ाफ़रान. दुनिया की सब से महँगी जड़ी-बूटियों में से एक. जिसे ख़ास तौर से कश्मीर की वादियों से चुना गया.

केसरी जीवन में ज़ाफ़रान के अरोग्यकर और सौंदर्यवर्धक गुणों के साथ-साथ ताज़ा आँवला और कई दूसरी जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं. यह सब मिलकर आपके शरीरगठन को मज़बूत करते हैं. शरीर के टिशूज़ को वृद्धावस्था में भी चुस्त बनाए रखते हैं और आज की तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी के तनावों से आपको मुक्त रखने में आपकी मदद करते हैं. तो आज ही से इसे अपनी आदत बना लीजिए. और जीवनभर बीमारियों से मुक़ाबला करने की शक्ति जुटा लीजिए. वृद्धावस्था में सेहत का अनमोल रत्न आप भी पा लेंगे, और सारी ज़िन्दगी, ज़िन्दगी से भरपूर तरो-ताज़ा रहेगी.

झंडु केसरी जीवन

Kesari-Jivan
Kesari-Jivan
PHARMACEUTICAL WORKS LTD.

रग-रग में जान — ज़िन्दगी की शान

ZP/8/244 HIN

कृष्णा रावत बनाम अनुसुइया शर्मा

झगड़ा दो महिला राजनीतिज्ञों का

मलीहाबाद से इंका की विधायक कृष्णा रावत और इंटक की अखिल भारतीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य और मजदूर नेता अनुसुइया शर्मा का आपसी विवाद अब मारपीट पर उतर आया है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और हत्या की कोशिश की रिपोर्ट कोतवाली हजरतगंत में लिखा चुकी हैं और दोनों ने मुख्यमंत्री से अपनी जान-माल की रक्षा करने की फरियाद भी की है। इन दोनों के बीच झगड़े की असली जड़ क्या है?

कोतवाली हजरतगंज
लखनऊ

कृष्णा रावत से खतरा: कोतवाली के सामने (और इनसेट में) अनुसुइया शर्मा

मुख्यमंत्री निवास से शुरू हुई दो कांग्रेसी महिलाओं की लड़ाई अब खुल कर सड़क पर आ गयी है। इनमें से एक महिला हैं मलीहाबाद से कांग्रेस-इ की बहुचर्चित विधायक कृष्णा रावत और दूसरी इंटक की अखिल भारतीय सलाहकार बोर्ड की सदस्या एवं तेजतर्रार मजदूर नेता अनुसुइया शर्मा।

मारपीट किसने की?: दोनों महिला राजनीतिज्ञ जब २८ अक्टूबर, १९८७ को लखनऊ के गोखले मार्ग पर मारपीट करने लगीं, तो अभूतपूर्व दृश्य उत्पन्न हो गया। घटना के बारे में अनुसुइया शर्मा ने रुंधे गले और आंखों से बहते आंसुओं के बीच हजरतगंज थाने में 'माया' प्रतिनिधि को बताया, "मैं कल मजदूर समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गयी थी। प्रधानमंत्री से मिलकर आज सुबह ही लखनऊ लौटी थीं। मैं सीधे अपनी बीमार मां को देखने बलरामपुर अस्पताल गयी। वहां से मैं रिक्शे पर बैठकर अपने कार्यालय उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम जा रही थी कि रास्ते में मुझे कांग्रेस की कार्यकर्ता विजया पंत मिल गयीं। मैं उनके साथ गोखले मार्ग स्थित सुलतानपुर पुलिस चौकी के समीप पहुंची थी कि यकायक सफेद रंग की एम्बेसेडर कार (यू०आई०वाई० २१४४) से कृष्णा रावत वहां पहुंची। कार में चार गुण्डे बैठे थे। मुझे देखते ही कृष्णा रावत चीखीं, 'खींचकर कार में डाल लो इसे।' और जब खुद कृष्णा रावत और उनके शेडो ने मुझे रिक्शे से नीचे खींचना शुरू कर दिया, तो विजया पंत ने मुझे पकड़ लिया और शेडो को डांट कर अलग कर दिया। कृष्णा रावत मुझे भद्दी-भद्दी गालियां देकर चप्पल से पीटने लगीं। मेरा शोर सुनकर कुछ राहगीर और सफाईकर्मी महिलाएं वहां आ गयीं। उन्होंने मुझे कृष्णा रावत के चगुंल से बचाया, अन्यथा वह मेरा अपहरण कर मेरी हत्या करवा देतीं।"

रिक्शा चालक राजकुमार और विजया पंत, अनुसुइया शर्मा के कथन की पुष्टि करते हैं। उधर विधायक कृष्णा रावत ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में लिखाई गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है, "मैं रिक्शे पर बैठकर अपने निवास स्थान ओ०सी०आर०—(पुराने विधायक निवास के बहुखण्डीय भवन) से निशातगंज जा रही थी। जवाहर भवन के निकट मुझ पर अनुसुइया शर्मा और एक महिला ने पीछे से हमला कर दिया। अनुसुइया के साथ स्कूटर नम्बर यू०एच०यू० ६३८८ पर दो युवक भी थे। अनुसुइया ने मेरे साथ मारपीट की और अपशब्द कहे, तो मैं जान बचाकर भाग निकली।"

जब कुछ पत्रकारों ने कृष्णा रावत से बात करनी चाही, तो उनका उत्तर था, "आप लोग मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं लिख सकते, अन्यथा मैं आपका अखबार सेंसर करा दूंगी।" एक छायाकार ने जब हजरतगंज कोतवाली के बाहर कृष्णा रावत का फोटो खींचना चाहा, तो वह बोलीं, "मैं कोई बाजारू महिला नहीं जिसकी सब जगह फोटो खिंचती रहे।"

कृष्णा रावत का अतीत: कृष्णा रावत विधायक बनने के पूर्व से ही काफी चर्चित रही हैं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मथुरा प्रसाद सिन्हा को उत्तर प्रदेश का सूचना निदेशक बनवाया था, तब कृष्णा रावत को लेकर श्री सिन्हा खासे चर्चित हुए थे। इसी कारण उन्हें सूचना निदेशक के पद से हटना पड़ा। जब १९८५ के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार छांटने और कांग्रेस-इ के टिकट बांटने की जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह पर थी, तब मथुरा प्रसाद सिन्हा ने प्रयास कर वी०पी० सिंह से कृष्णा रावत को मलीहाबाद सुरक्षित चुनाव क्षेत्र से टिकट दिलवाया था। भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय धर्मवीर से भी रावत के गहरे संबंध थे। धर्मवीर ने भी उन्हें टिकट देने की सिफारिश की थी। इसके पूर्व इस क्षेत्र से जनता पार्टी के मानसिंह आजाद विधायक थे। कृष्णा रावत ने यह सीट कांग्रेस के लिए जीत ली।

विधायक चुने जाने के बाद कृष्णा रावत ने भारतीय जनता पार्टी के एम०एल०सी० ज्ञान चन्द द्विवेदी के ओ०सी०आर० स्थित निवासस्थान पर जबरन कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने श्री द्विवेदी का सारा सामान भी अपने आदमियों के जरिये बाहर फेंकवा दिया। जब इस घटना की सूचना मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को दी गयी, तो वह बहुत नाराज हुए।

छोटे से लेकर बड़े नेताओं और मंत्रियों तक कृष्णा रावत की पहुंच का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। इस सिलसिले में विश्व प्रसिद्ध मलीहाबादी आमों की भूमिका अहम है। जिन दिनों मलीहाबाद के बागों में आमों की बहार रहती है, उन दिनों कृष्णा रावत की व्यस्तता देखते बनती है। आमों की भरी पेटियां नेताओं और मंत्रियों के बंगलों पर पहुंचाकर जब वह लौटती हैं, तब उनका चेहरा चमकता रहता है। आमों के सहारे उनकी घुसपैठ का यह आलम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री निवास तक अपने रसूक बना लिये हैं।

कृष्णा रावत कितनी दबंग हैं, इसकी जानकारी अक्तूबर, १९८६ की उस घटना से मिलती है, जिसमें उन्होंने एक पुलिस उपाधीक्षक पर अपनी चप्पल तान ली थी। इस घटना ने पुलिस अधिकारियों में काफी रोष पैदा कर दिया था। उन्होंने इस बारे में अपने उच्चाधिकारियों से सख्त विरोध किया था। हुआ यह कि कृष्णा रावत के अंगरक्षक के खिलाफ कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि वह उन्हें आते-जाते छेड़ता है। इस शिकायत की सचाई की जांच का भार मोहनलालगंज के क्षेत्राधिकारी महेन्द्र सिंह राठौर को सौंपा गया। श्री राठौर ने अपनी जांच में अंगरक्षक सिपाही को दोषी पाया। सिपाही ने कृष्णा रावत से सिफारिश करवाई। जब सिफारिश के सिलसिले में कृष्णा रावत श्री राठौर से मिलीं, तो उन्होंने लाचारी जाहिर करते हुए सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। इस पर कृष्णा रावत ने उन पर अपनी चप्पल तान ली। विधायक होने की वजह से बाद में यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों ने दबा दिया। इतना ही नहीं कृष्णा रावत की खटपट राज्य सभा में कांग्रेस-इ की सदस्य श्रीमती कैलाशपति से भी हो चुकी है। रावत को आपत्ति है, "कैलाशपति उनके विधानसभा क्षेत्र में जनसम्पर्क क्यों करती हैं ?" उल्लेखनीय है कि कैलाशपति मलीहाबाद सुरक्षित क्षेत्र से लोकसभा की सदस्या रह चुकी हैं।

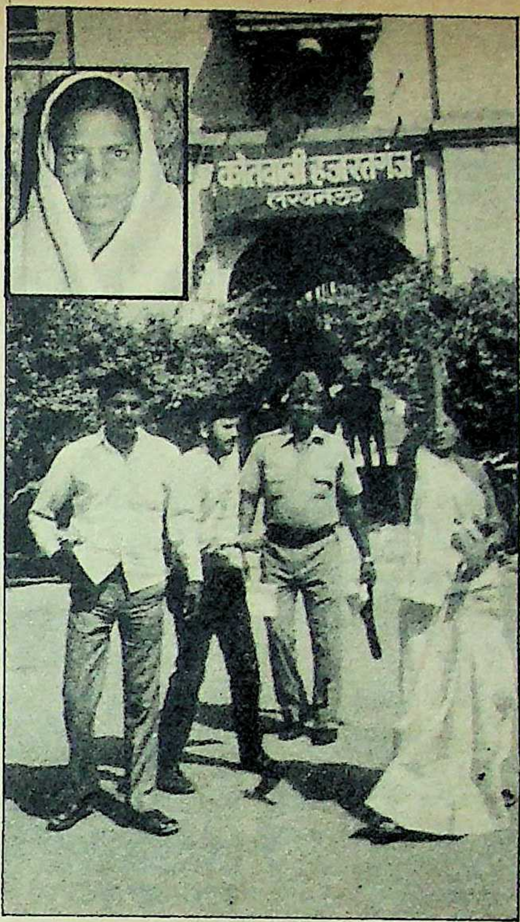

अनुसुइया ने मार डालने की कोशिश की: रिपोर्ट लिखाने के बाद कोतवाली से निकलतीं (इनसेट) कृष्णा रावत

झगड़े का असली कारण: आखिर, कृष्णा रावत और अनुसुइया शर्मा में कब, क्यों और कैसे ठन गयी, यह भी एक दिलचस्प किस्सा है। अनुसुइया शर्मा का कहना है, "१५ अगस्त, १९८७ को मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री कई विधायकों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं थी। तभी कृष्णा रावत आ पहुंचीं। कुछ विधायकों ने कहा "आइये रावतजी, एक महिला से दो महिला भलीं।" बस फिर क्या था, कृष्णा रावत का मूड खराब हो गया। उन्होंने पलट कर उत्तर दिया, "मैं उन औरतों में नहीं हूं जो घुसकर मुख्यमंत्री के पास बैठती हैं।" बात आयी-गयी हो गयी।

सुश्री शर्मा ने आगे बताया, " २० अगस्त को राजीवजी के जन्म दिवस के सिलसिले में दिल्ली जाने से पहले मैं १९ अगस्त की शाम को मुख्यमंत्री के एनेक्सी स्थित कार्यालय पहुंची, ताकि मुख्यमंत्री से विचार विमर्शकर मजदूरों की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करा सकूं। कृष्णा रावत ने मुझे लेकर वही आपत्ति की कि विधायकों के मिलने के तयशुदा समय में गैरविधायक मुख्यमंत्री कार्यालय में क्यों मौजूद हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें डांट दिया और कहा, 'मैं सिर्फ विधायकों का ही नहीं सबका मुख्यमंत्री हूं। यह भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं।' बस तभी से कृष्णा रावत मुझसे खुदंक खाने लगी।"

खुंदक का सिलसिला आगे बढ़ता गया। दिल्ली स्थित यू०पी० भवन में ८ अक्तूबर, १९८७ को गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित की उपस्थिति में कृष्णा रावत और अनुसुइया शर्मा आपस में झगड़ पड़ीं। फिर दोनों प्रधानमंत्री निवास में भी जाकर लड़ गयीं। कृष्णा रावत ने जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की, तो उन्होंने रावत को पुनः डांट दिया।

इसी के बाद कृष्णा रावत ने चाणक्यपुरी थाने में अनुसुइया के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की रिपोर्ट लिखाई थी। अनुसुइया कहती हैं, "वास्तव में कृष्णा रावत मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलती हैं। इसी कारण मेरे पीछे पड़ी हैं। वह हरिजन होने का फायदा उठाकर मुझ पर झूठे आरोप लगाती हैं।"

अनुसुइया शर्मा आवश्यक वस्तु खाद्य निगम में लिपिक हैं। उनका आरोप है कि यह सारा झगड़ा निगम के अध्यक्ष डा० यू०पी० सिंह के इशारे पर हो रहा है। डा०यू०पी० सिंह ने निगम का अध्यक्ष बनने के बाद यात्राओं में गैर जिम्मेदाराना ढंग से अनाप-शनाप खर्च किया है और मैंने यूनियन नेता होने के कारण इसका विरोध किया। चूंकि, मैंने डाक्टर साहब के खर्चों पर आपत्ति की, इसलिए डा०यू०पी० सिंह मेरा विरोध कृष्णा रावत से कराने लगे।

अनुसुइया शर्मा कद, छवि और रूप रंग में कृष्णा रावत की तरह ही हैं। वह एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में घुसी थीं। उन्होंने विधायक डी०एच० अंसारी का दामन पकड़ा और उन्हीं के साथ दारुलशफा स्थित विधायक निवास के कमरा नम्बर ६ में रहती हैं। यहां तक कि उन्हें कहीं भी जाना होता है, तो विधायक अंसारी उनके साथ रहते हैं।

जब बाल्टी बाबा खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष थे तब, अनुसुइया शर्मा उनकी खास हो गयीं। डा०यू०पी० सिंह के निगम के अध्यक्ष पद पर आते ही अनुसुइया शर्मा ने अपनी यूनियन के माध्यम से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उधर कृष्णा रावत ने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग उनकी छवि बिगाड़ने में लगे हैं। इन्हीं लोगों ने अनुसुइया शर्मा नामक एक महिला के माध्यम से मुझ पर हमला कराया है। एक माह के अन्दर यह दूसरा हमला है। पहला हमला ९ अक्तूबर, १९८७ को अनुसुइया शर्मा और उनके साथियों ने किया था। इस हमले में मेरा गला दबाकर मेरी हत्या का प्रयास किया गया था। लखनऊ में हुई मार-पीट में मेरा हाथ टूट गया है। मुझे जान-माल का गंभीर खतरा है, अतः मेरी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाये।

फिलहाल, दो कांग्रेसी महिलाओं का यह झगड़ा लोगों के चटखारे का विषय बन गया है। परदे के पीछे से कई वरिष्ठ कांग्रेसी इसे हवा देकर मजा ले रहे हैं। देखना है, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह इनके झगड़े का निपटारा कैसे करते हैं ?

छाया: मनमोहन शर्मा —**निशीथ जोशी**

देहरादून-मसूरी विकास महायोजना

एक विवादित महायोजना

निर्मित होते बहुमंजिला भवन: माल रोड, मसूरी पर ११ मंजिला हेमकुण्ड एपार्टमेंट

सरकार भी पीछे नहीं: गढ़वाल विकास निगम की बहुमंजिली इमारत

सरकार ने पर्वत नगरी मसूरी सहित दून घाटी के विकास एवं सुंदरीकरण के लिए यह कैसी महायोजना बनायी है कि हरे-भरे बेशकीमती हजारों पेड़ों को काटकर वहां आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र बनाये जा रहे हैं और लोगों को अपनी ही भूमि पर बने मकानों पर जुर्माना देना पड़ रहा है। जुर्माना न देने पर उनके मकान गिराये जा रहे हैं, दूसरी ओर स्वयं राज्य सरकार एवं प्रभावशाली लोग मसूरी में बहुमंजिली इमारतें बनाकर इसके नैसर्गिक सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं। सर्वाधिक रोचक तथ्य यह है कि सरकारी गजट में अभी यह महायोजना नियमत: लागू ही नहीं हुई है, फिर भी सरकारी अधिकारियों द्वारा महायोजना के नाम पर स्थानीय लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। राज्य सरकार दून घाटी का सुंदरीकरण कर रही है या इसे उजाड़ने पर तुली हुई है? :

उत्तर भारत की सुन्दर और सुरम्य दून घाटी तथा उसमें बसी पर्वतनगरी मसूरी आज अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रही है। वहां के सीधे-सादे निवासी कथित भ्रष्ट अधिकारियों से मसूरी की लाज बचाने के लिए दर-दर गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई 'कृष्ण' नहीं मिला है। नियोजित विकास के नाम पर गठित देहरादून-मसूरी महायोजना, इन्हीं कथित भ्रष्ट अधिकारियों के कारण अपने प्रथम चरण की शुरुआत में ही न केवल विवाद का विषय बन गयी है, वरन दून घाटीवासियों के लिए अभिशाप समझी जाने लगी है। जहां एक ओर यह महायोजना अपनी तुगलकी कार्यप्रणाली के कारण निरीह और गरीब पर्वतवासियों पर कहर ढा रही है, वहीं अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस महायोजना की परिधि में मसूरी नगरी है भी या नहीं।

हाल ही में गढ़वाल मंडल के आयुक्त सुरेन्द्र सिंह पांगती ने एक मुकदमे में निर्णय देते हुए कहा था कि यह महायोजना अभी लागू नहीं है। उनके निर्णय का आधार यह था कि चूंकि राज्य सरकार की ओर से इस महायोजना की रूपरेखा से संबंधित कोई अधिसूचना (गजट) जारी नहीं हुई है, इसलिए इस महायोजना का लागू होना अभी माना नहीं जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह तथा सचिव यू०डी० चौबे, पांगती के निर्णय को चुनौती देते हुए कहते हैं, "यह महायोजना ८ मई, १९८५ से लागू हो चुकी है। उसके लागू होने की सूचना उसी समय दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गयी थी। हमने आयुक्त के निर्णय को चुनौती देते हुए ऊपर अपील की है।"

महायोजना: दरअसल, उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में बढ़ते अवैध कब्जों तथा अनियोजित विस्तार को रोकने के उद्देश्य से वर्ष १९७३ में राज्य सरकार ने नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम लागू किया था। इसी के साथ ही लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा सहित कई अन्य बड़े नगरों में विकास प्राधिकरण गठित कर दिये गये। इन प्राधिकरणों का काम अनियोजित विस्तार को रोकना तथा नजूल की जमीनों की देखभाल करना था। पहले यह काम नगरपालिकाओं के अधीन था।

लगभग २१३० वर्ग किलोमीटर की परिधि में बसी तथा २९.५७ से ३०.३२ उत्तरी अक्षांश और ७७.३५ से ७८.२० देशान्तर तक फैली दून घाटी भी समय के साथ-साथ विकास की ओर बढ़ रही थी। वर्ष १९८१ की जनगणना के अनुसार दून घाटी की आबादी ६ लाख, ७४ हजार तक पहुंच गयी थी जो १९८७ के प्रारंभिक दिनों में बढ़कर ७ लाख, ३५ हजार तक हो गयी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से निर्मित हो रहे भवन, यातायात

साधनों की बहुतायत को देखते हुए राज्य सरकार ने दून घाटी में अनियंत्रित विस्तार को रोकने के उद्देश्य से वर्ष १९८४ में दूसरे शहरों की तरह देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया। इसी के साथ ही दून घाटी के विकास के लिए एक महायोजना की भी घोषणा कर दी। इस महायोजना में देहरादून और मसूरी के शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के १८५ गांवों सहित देहरादून छावनी, क्लेमेन्टाउन छावनी, अधोईवाला ग्रामसभा आदि क्षेत्र भी शामिल कर लिये गये। इस महायोजना की घोषणा और प्राधिकरण के गठन के साथ ही दून घाटी के लोगों पर अधिकारियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया। दरअसल, इस महायोजना के लागू होते ही ग्रामप्रधानों के भूमि सम्बन्धी अधिकार समाप्त कर दिये गये। किसानों से जबरन ढाई बीघा से अधिक भूमि लिये जाने तथा उपजाऊ भूमि पूंजीपतियों, व्यापारियों के हाथों में चले जाने से किसानों में रोष व्याप्त हो गया। लगभग १५० किसानों को महायोजना की इस तुगलकी नीति के विरुद्ध उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। महायोजना की कार्यवाही के विरुद्ध किसानों और भुक्तभोगियों की अगुवाई यहां के निर्विवाद किसान नेता कुशल पाल सिंह, मुजफ्फरनगर के किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत की तर्ज पर कर रहे हैं। कुशल पाल सिंह बताते हैं, "इस महायोजना के योजनाकारों ने आवासीय क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट तथा ग्रीन बेल्ट को आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। योजनाकारों की इस सनक के कारण हजारों की संख्या में लीची के पेड़ों और चाय-बागानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है।" उनका कहना है, "एक ओर तो सरकार बिना अनुमति पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध लगाये हुए है, दूसरी ओर इस इलाके के सैकड़ों बेशकीमती पेड़ स्वयं कटवा रही है। लगभग ६०० हरे पेड़ों का मण्डी समिति, चाय बागानों और टिहरी विस्थापितों के नाम पर सफाया करा दिया गया। निरंजनपुर चुंगी के पास सहारनपुर रोड पर लीची के लगभग ६०० पेड़ कटवाने की योजना अधिकारियों ने बनायी है। यदि यही स्थिति रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब लीची के लिए प्रसिद्ध देहरादून स्वयं भी लीची का मोहताज हो जायेगा।"

विकास या उत्पीड़न : शहरी क्षेत्र में विकास के नाम पर इस महायोजना के तहत बने बनाये मकानों को गिराने, नये मकानों के निर्माण के लिए लूट-खसोट तथा विकास शुल्क के नाम पर जबरिया थोपी जानेवाली राशि के कारण यह महायोजना नागरिकों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। भवन-स्वामियों को बिना नक्शे का निर्माण होने के नाते (भले ही वे प्राधिकरण गठन से पूर्व निर्मित हों) १ रुपए, १० पैसे प्रति वर्गमीटर की दर से अपनी ही भूमि पर बने मकानों पर जुर्माना तथा पूरी जमीन पर २५ रुपए प्रति वर्ग फिट के हिसाब से विकास शुल्क न चुकाने पर प्राधिकरण द्वारा उन मकानों को गिराने के आदेश जारी किये गये। ऐसे लगभग २ हजार मकानों को तोड़ने की नोटिसें प्राधिकरण ने जारी कीं। इस प्रकरण में चपरासी से लेकर अधिकारी तक मालामाल हुए।

प्राधिकरण की इस कार्यवाही का नागरिकों ने जमकर विरोध किया। क्यारकुली भट्ठा निवासी ६० वर्षीय कलम सिंह रावत की अध्यक्षता में एक जन संघर्ष समिति का गठन किया गया। बाद में इस समिति को 'दून जन-हित संघर्ष समिति' का नाम देकर राजपुर रोड निवासी गिरीश चन्द्र जुयाल, एडवोकेट तथा पी०एस० नेगी ने जन-आंदोलन की घोषणा की। मार्च, १९८५ से शुरू हुआ, यह आंदोलन अभी जारी है।

इस महायोजना में कृषि भूमि को आवासीय स्थलों तथा आवासीय स्थलों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के अलावा जो सबसे विचित्र बात शामिल है, वह है, यहां की दो नहरें। योजनाकारों ने स्वतंत्रता से भी पहले बनी इन दो नहरों, बीजापुर कैनाल तथा रायपुर फीडर को प्राधिकरण के मानचित्र में नहीं दर्शाया है, जबकि इन नहरों द्वारा हजारों एकड़ भूमि सिंचित होती है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने समतल एवं अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्र कांवली, निरंजनपुर, ब्राह्मणवाला, माजरा, सेवलाकलां, पित्थुवाला, अजबपुरकलां, अजबपुरखुर्द, माथरावाला, पथरीबाग आदि को आबादी के लिए आरक्षित कर लिया है। प्राधिकरण की इस कार्यवाही से इन जमीनों पर ४०-५० वर्षों से खेती करते आ रहे कृषकों के समक्ष भारी संकट आ पड़ा है। इसके विपरीत सिनोला, गुनियाल, पुडकल, करात, मरोठा, नांगल, दूधली, गुजराडा, डाण्डा लखौंड, मुधोवाला, ननूलखेड़ा, आमवाला आदि गांवों की बंजर और ऊसर पड़ी जमीन को कृषि योग्य घोषित किया गया। इसे योजनाकारों की सनक ही कहा जा सकता है।

नगरीय क्षेत्रों में विकास शुल्क की दर जो नगरपालिका के कार्यकाल में न के बराबर थी, प्राधिकरण के दौरे में ३६ रुपए से ५२ रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गयी। इसी तरह मानचित्र शुल्क की दर भी २० हजार तक पहुंच गयी थी जो काफी शोरशराबे के बाद कुछ कम हुई। १९ अक्तूबर, १९८६ को प्राधिकरण द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गयी कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत हुए बिना क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। इसी के बाद मकानों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। लगभग ४०० मकानों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान मकान मालिकों को बुलाकर सुलह-सपाटे की बात शुरू हुई। बताया जाता है कि इसी तरह सुलह सपाटे के नाम पर भ्रष्ट अधिकारी अंधी कमाई करने में लगे हैं।

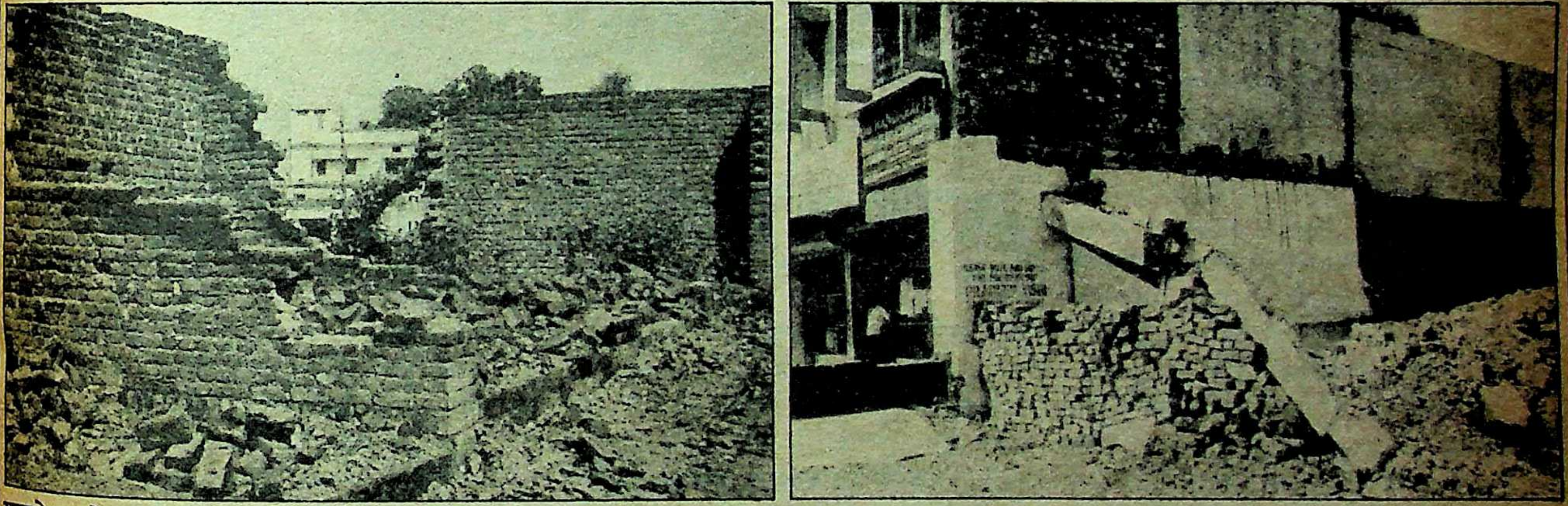

महायोजना के नाम पर ढहते भवन : (बायें) राजपुर रोड पर तोड़ी गयी दुकानें, (दायें) चकराता रोड निवासी इंतजार अहमद का ढहा मकान

यमुना स्कीम सिंचाई विभाग के कर्मचारी इंतजार अहमद का ५३, चकराता रोड स्थित मकान प्राधिकरण ने ढहा दिया। इंतजार अहमद वर्ष १९५२ से इस जगह सपरिवार रहते आ रहे थे। उनका यह मकान जब बना था, उस समय प्राधिकरण का कोई अस्तित्व नहीं था। ३० दिसम्बर, १९८६ को उन्हें तथाकथित अवैध निर्माण के लिए ६१ हजार रुपए की राशि प्राधिकरण में बतौर जुर्माना फौरन जमा करने का आदेश दे दिया गया। वह कुछ फरियाद करते, इसके पूर्व ही अगले दिन ३१ दिसम्बर को उनका पूरा मकान प्राधिकरण के कारिन्दों ने ढहा दिया। अल्प-वेतनभोगी इंतजार अहमद अपने पांच अबोध बच्चों और परिवार के चार वयस्क सदस्यों के साथ

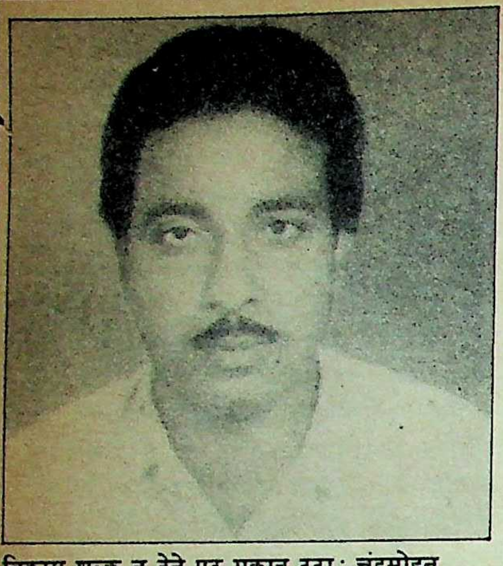

विकास शुल्क न देने पर मकान टूटाः चंद्रमोहन

अपनी ही जमीन पर बिना छत के हो गये।

इंतजार अहमद बताते हैं, "५० हजार रुपए की लागत से बने मकान का जुर्माना ६१ हजार रुपए दे पाना मेरी औकात के बाहर की बात थी।" वह कहते हैं, "मकान न तोड़े जाने के लिए २७ नवम्बर को मेरे भाई इफ्तखार अहमद को एक पर्ची लिखकर प्राधिकरण के अवर अभियन्ता ने बुलवाया था। उन्होंने २० हजार रुपए सुविधा शुल्क के तौर पर मांगे थे। उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था, नहीं तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता।"

सुविधा शुल्क का कहर: २७२, खुदबुदा निवासी चंद्रमोहन ने २० मई, १९८६ को प्राधिकरण द्वारा पास नक्शे के आधार पर अपना मकान बनवाया था। लगभग डेढ़ लाख की लागत से बने उनके इस मकान पर भी ७ फरवरी, १९८७ को प्राधिकरण की गाज गिरी और मकान तोड़ दिया गया। इस सम्बन्ध में चंद्रमोहन के पिता ६२ वर्षीय राजाराम बताते हैं, "मेरा मकान न तोड़ने के लिए अधिकारियों ने मुझसे १० हजार रुपए बतौर सुविधा शुल्क के मांगे थे। उस समय मैं इतनी बड़ी राशि से उन अधिकारियों की ऊपरी आमदनी नहीं करा सका, लिहाजा यह खमियाजा भुगतना पड़ा।" चंद्रमोहन ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई के विरुद्ध जिला न्यायालय में दावा ठोंक रखा है।

अजबपुरकलां निवासी आर०सी० बछेती द्वारा २६ अक्तूबर, १९८० को खरीदे गये तथा १९८२ में दाखिल-खारिज कराकर मकान बनाने के बाद इस महायोजना के अधिकारियों ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की। ६ मार्च, १९८७ को प्राधिकरण द्वारा उनका मकान गिराने का आदेश पारित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में श्री बछेती बताते हैं, "यह गांव नगरपालिका सीमाक्षेत्र से बाहर है, इसलिए पहले नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह मकान मैंने महायोजना लागू होने के पूर्व बनवाया था।" फिलहाल श्री बछेती ने प्राधिकरण के इस आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा गढ़वाल मण्डल के आयुक्त एस०एस० पांगती के यहां से स्थगनादेश प्राप्त कर अपने मकान को टूटने से बचा लिया है।

बहुमंजिली इमारतें: ऐसे लगभग डेढ़ सौ लोगों ने महायोजना के आदेशों को अदालत में चुनौती दे रखी है। यह हुक्मरान जहां एक ओर भवन-स्वामियों को थोड़ी बहुत कमियों के कारण इतना बड़ा दण्ड दे रहे हैं, वहीं पूंजीपतियों व परिचयवालों को पूरा सहयोग पहुंचा रहे हैं। मसूरी में बनी बहुमंजिला इमारतों और होटलों की बढ़त इसका ज्वलन्त उदाहरण है। बाबर रोड, दिल्ली की संस्था इन्द्रप्रस्थ बिल्डर्स द्वारा बहुमंजिला होटल के निर्माण की स्वीकृति देने में प्राधिकरण ने नियम कानून को धता बता दिया। ग्रामीणों और जनसामान्य के विकास शुल्क एवं अन्य मदों के नाम पर भारी धनराशि उगाही जा रही है। इसके विपरीत कुछ खास बड़े लोगों से मात्र दो सौ प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा विकास शुल्क के नाम पर सिर्फ ४,९८१ रुपए की राशि ही ली गयी है। यही नहीं, बल्कि विकास शुल्क के नाम पर क्षेत्र के लोगों से तो २५ रुपए प्रतिवर्ग फुट सामान्य भवनों से तथा व्यावसायिक भवनों के लिए इससे दुगनी वसूली की जा रही है, जबकि इन्द्रप्रस्थ बिल्डर्स से यह धनराशि १० रुपए की दर से ली गयी।

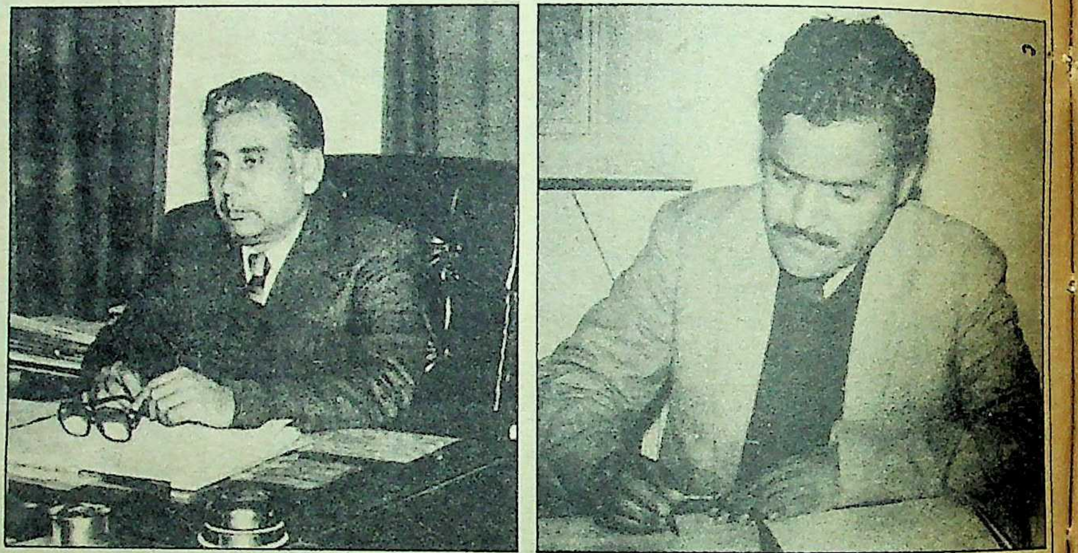

विकास का कार्य चालू है: प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रताप सिंह एवं सचिव यू०डी० चौबे

इसी तरह माटक्लेअर, हेमकुंड अपार्टमेंट, दुर्गा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, रत्रिका अपार्टमेंट, एम०एस० अपार्टमेंट, होपेकुबेज, बेलमोगा अपार्टमेंट जैसे एक-से-एक भवन-निर्माता बाहर से आकर लुभावनी अपीलों के साथ मसूरी के सौंदर्य पर गगनचुम्बी इमारतों के साथ छाये जा रहे हैं। मसूरी के नागरिकों का आरोप है कि यहां भवन-निर्माताओं की गतिविधियां इस महायोजना के लागू होने के बाद ही बढ़ी हैं।

मसूरी में इस समय आठ बहुमंजिली इमारतें बनानेवाली कम्पनियां यहां की नैसर्गिकता पर आंखे गड़ाये हुए हैं। मसूरी नगरपालिका भवन-निर्माण नियम—१९ (डी) के अनुसार मसूरी से दून घाटी के जिन-जिन स्थानों के दृश्य दिखाई देते हैं, वहां पर कोई भी निर्माण सड़क की सतह से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत आज अनेक ऐसे निर्माण सरकारी गैरसरकारी स्तर पर हो रहे हैं। राज्य सरकार की एक बहुमंजिली इमारत है 'गढ़वाल विकास निगम'—उसने भी इस नियम को ताख पर रख दिया है।

दरअसल, आरोप लगाया जाता है कि मसूरी में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिए वर्ष १९८१-८२ में यहां तैनात जिलाधिकारी ओ०पी० शर्मा सीधे तौर पर दोषी हैं। वास्तव में इन इमारतों के निर्माण की अनुमति देने की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उस समय तत्कालीन स्वायत्त-शासन मंत्री कृष्ण गोयल ने इन इमारतों के निर्माण पर कड़ी आपत्ति करते हुए जिलाधिकारी से जवाब-तलब किया था। बावजूद इसके जिलाधिकारी ओ०पी० शर्मा ने ३० अगस्त, १९८२ को प्रशासक की हैसियत से हेमकुंड अपार्टमेंट की ग्यारह मंजिली इमारत का नक्शा पास कर दिया। अब इसी इमारत का हवाला देते हुए अन्य कोलोनाइजर्स अदालत से स्थगनादेश लेकर मसूरी में पैर जमा चुके हैं।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रशासक प्रताप सिंह इस सम्बन्ध में बताते हैं, "ये इमारतें महायोजना लागू होने से पहले ही बन चुकी थीं। महायोजना में कुछ विसंगतियां होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसके निवारण के लिए हमने एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। इन विसंगतियों की जांच के लिए एक परीक्षा समिति भी बनायी गयी है।" एक ओर तो प्रताप सिंह इन इमारतों को महायोजना लागू होने से पूर्व की बनी बताकर अपना पीछा छुड़ाते हैं, दूसरी ओर उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है कि अन्य उन मकानों को क्यों तोड़ा गया जो महायोजना के पहले बने थे।

अभिसप्त विकास: जहां एक ओर मसूरी में बहुमंजिली इमारतों का अभिसप्त विकास हो रहा है, वहीं यहां के लोग पानी, विद्युत, सफायी और

आवास जैसी जीवन की बुनियादी सहूलियतों से वंचित होते जा रहे हैं। मसूरी में हो रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों से तथा वनों के कटान और पहाड़ियों के दोहन से जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्प्रिंग रोड पर पानी के स्रोतों के आसपास इमारतों के बन जाने से ये स्रोत सूखते जा रहे हैं। वैसे भी मसूरी में पानी के इनेगिने स्रोत हैं। १९२० में अंग्रेजों ने यहां २ लाख, ४ हजार गैलन भण्डारण क्षमतावाली दो टंकियां बनवायी थीं। आज जनसंख्या दूनी हो जाने के बावजूद टंकियों की इस क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। नतीजतन, यहां के लोगों को सुबह-शाम एक-एक घंटे ही पानी नसीब हो पाता है। जल-संकट दूर करने के लिए दस वर्ष पूर्व मसूरी बोर्ड ने अगलाड नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनायी थी। यह योजना आज तक गढ़वाल जल-संस्थान की फाइलों में कैद है। सर्दियों में मसूरी को १० लाख गैलन तथा गर्मियों में ३० लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत इस समय यहां के लोगों को ८-९ लाख गैलन पानी ही उपलब्ध हो पाता है।

यही हालत यहां की सफायी व्यवस्था की है। आजादी के बाद से यहां कोई नयी सीवर लाइन नहीं डाली गयी, इस कारण अधिकतर लोगों को अपना सैप्टिक टैंक बनाना पड़ रहा है। सड़क और पार्कों की दुर्दशा भी छिपी नहीं है। खुले में गंदगी के अम्बार जहां-तहां देखे जा सकते हैं।

प्राधिकरण के प्रशासक प्रताप सिंह और सचिव यू०डी० चौबे बताते हैं, "गत वित्तीय वर्ष में विकास शुल्क के माध्यम से प्राधिकरण को ३० लाख रुपए से अधिक की आय हुई है। हम इस समय १० सड़कें और ५ पार्कों का निर्माण करवा रहे हैं। राजपुर रोड पर व्यावसायिक केन्द्र तथा आवासीय योजनाओं पर भी काम चल रहा है। सड़क, प्रकाश व सफायी के लिए सरकार की ओर से ६ लाख रुपए मिले हैं, काम चालू है।"

प्रदेश के पर्यटन राज्यमंत्री प्रमोद तिवारी मानते हैं कि मसूरी को और सुन्दर बनाने के साथ-साथ आस-पास के पर्यटक-स्थलों के विकास की भी जरूरत है। इस दृष्टि से मसूरी के निकट झड़ी पानी, खट्टा पानी, जार्ज एवरेस्ट हाउस, धनौलटी, कछूखाल आदि मनोरम स्थलों को विकसित करने की योजना है। फिलहाल, अभी तक ये योजनाएं कागजों पर ही बन रही हैं।

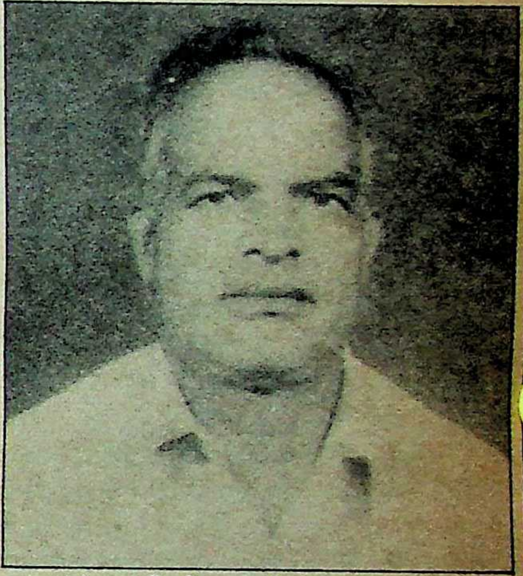

जन-आंदोलन की घोषणा: गिरीश चन्द्र जुयाल

देहरादून और मसूरी में समुचित विकास की यह महायोजना लागू है या नहीं, यह विवाद अभी न्यायालय और सरकार की फाइलों में बन्द है। जन आन्दोलन ने इस महायोजना की महत्ता पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि यदि महायोजना लागूं है, तो जनसामान्य की बुनियादी सहूलियतों पर कितना काम हुआ? और नहीं लागू है, तो पहले के बने आवासीय स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई क्यों हुई?

फिलहाल इस महायोजना का राज्य गजट में प्रकाशन न होने के कारण देहरादून-मसूरी के लोग तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को अवैध मानते हैं। यही वजह थी कि गत २८ मार्च, १९८६ को प्रदेश की नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती पद्मा सेठ की अध्यक्षता में होनेवाली दूनघाटी महायोजना की बैठक नागरिकों के आंदोलन के कारण विफल हो गयी। नागरिकों का मानना है कि अगर महायोजना मंजूर कर ली गयी, तो प्राधिकरण के हुक्मरान सुविधा-शुल्क के नाम पर स्थानीय लोगों का शोषण करते रहेंगे।

—सुरेश द्विवेदी और रामप्रताप मिश्र, देहरादून से

छाया: डी०एस० पाण्डेय

पर्यावरण और सहूलियतों का हनन

अपने नैसर्गिक आकर्षण के कारण पर्वतों की रानी मसूरी में जनसंख्या, वाहनसंख्या, भवनसंख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। यहां की बेहतरीन जलवायु इस इजाफे का कारण है। मसूरी का अधिकतम तापमान ३२ डिग्री सेल्सीयस तथा न्यूनतम २ डिग्री सेल्सीयस तक रहता है। घनी पहाड़ियों के बीच यह तापक्रम अधिकतम २२ डिग्री सेल्सीयस तथा न्यूनतम ०.८ डिग्री सेल्सीयस तक पहुंच जाता है।

यह मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य का ही आकर्षण है कि यहां आनेवाले पर्यटकों की संख्या इजाफे के दौर में है। २२ वर्ष पूर्व १९६५ में पूरे साल में यहां आनेवाले पर्यटकों की संख्या २,८४,२८२ थी जो १९८५ में बढ़कर ९,४६,११७ और अब (१९८७) सितम्बर माह तक ११ लाख तक पहुंच गयी है। वर्ष १९८६ के जून माह में ही यहां १,८८, ५६१ पर्यटक आये थे, जबकि इस वर्ष जून माह में यह संख्या डेढ़ गुना बढ़कर २,०३,४४८ हो गयी।

एक ओर मसूरी आनेवाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन महायोजना के हुक्मरान इन्हें सहूलियतें देने या सौंदर्य विकास करने की जगह अपने सुविधा-शुल्क की प्राप्ति के हथकण्डे अपनाने में लगे हुए हैं। बहुमंजिली इमारतों, पहाड़ियों के दोहन से जहां पानी के स्रोत छिन्न-भिन्न हुए, वहीं इस महायोजना के योजनाकार यहां के बाशिन्दों और पर्यटकों के लिए पेयजल मुहैया नहीं करा सके हैं। हालात यहां तक हैं कि सीजन में झरनों की इस पर्यटन स्थली में पर्यटकों को गला तर करने के लिए एक गिलास पानी के ५० पैसे से एक रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ती है।

कुछ वर्ष पहले कुछ पर्यावरण-प्रेमियों के सत्प्रयास ने मसूरी में स्थित ५० से अधिक चूनाखाने बन्द करवाकर पहाड़ों की इस रानी को उजड़ने से बचा लिया था। भारत सरकार ने भी रुचि ली थी। पर्यावरण के बचाव के लिए विशेष रूप से गठित 'हिमालयन फौज' (इको टास्क फोर्स) के जवान दिन रात मेहनत करके उजड़ी पहाड़ियों पर फिर से हरियाली बिखेरने में लगे हुए हैं। इसके विपरीत भारत सरकार के गृह-मंत्रालय की ही फौज 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस' का इन पहाड़ियों पर जमावड़ा पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। 'पैरा मिलेटरी फोर्स' के इन जवानों द्वारा दिन रात किये जानेवाले भयंकर विस्फोटों, धुंआधार धमाकों और गोलाबारी से मकानों की नींवें तक हिल जाती हैं। इन कानफोड़ू विस्फोटें से पहाड़ियों के स्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। यह फोर्स १३० एकड़ से ज्यादा की भूमि पर काबिज है। स्प्रिंग रोड के नीचे 'ऐस्टल ऐस्टेट' में भी पिछले ५ वर्षों से इस फौज ने कब्जा कर रखा है। वैसे भी मसूरी जैसी पर्यटक-स्थली में इस फोर्स का रहना खतरनाक है। यहां इनकी हलचलों की गोपनीयता बरकरार रख पाना संभव नहीं है।

मसूरी के पर्यावरण और सौन्दर्य को सबसे गम्भीर खतरा पहाड़ियों पर बननेवाली बिल्डिगों की बढ़ती हुई संख्या है। बाहर से आयी पूंजीपति बिल्डर्स संस्थाएं पहाड़ियों को सस्ते में खरीदकर, लुभावने वायदों के साथ बिल्डिगें बनवाकर ऊंचे दामों पर बेच रही हैं। इमारत बनेगी, तो वृक्ष कटेंगे ही। वन विभाग द्वारा प्रति पेड़ पांच सौ रुपए जुर्माना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि एक पेड़ से कम-से-कम ५० क्विंटल लकड़ी मिलती है और उसे प्रति क्विंटल दो सौ रुपए में बेचकर वन विभाग के जुर्माने को ठेंगा दिखा दिया जाता है।

रामनाथ मुंशी

बात अपने तक ही रखियेगा

'मुंशी' एक बहुत पुराना नाम है, या यों कह लीजिए कि, 'पद' और 'उपनाम' दोनों है। चाहे मुंशी प्रेमचंद हों या फिर बंगाल के प्रिय रंजन दास मुंशी। अमृतसर के तोंताराम मुंशी हों या स्वर्गीय कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। मुंशी तो बस मुंशी ही होता है, चाहे वह थाने का हो या कांजी हाउस का। लेकिन हमारे मुंशी हैं—रामनाथजी। इन्हें चाहे आप रामनाथ मुंशी कहिए या फिर मुंशी रामनाथ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में आजकल उनका रुतबा बढ़ गया है। जितनी बार भी आप उन्हें देखेंगे, हर बार उनके चेहरे का रंग और भाव बदला हुआ मिलेगा, ठीक उसी प्राणी की तरह, जिसकी तुलना लोग-बाग जरा-जरा सी बात पर रंग बदलने वाले के रूप में करते हैं।

तो भाई, हमारे मुंशीजी पहले दारू के 'मुंशी' थे—यानी आबकारी मंत्री। थे तो दारू मंत्री, लेकिन अंगूर की बेटी को हाथ तक नहीं लगाते थे। शायद इसी वजह से उन्हें गन्ने का भी मुंशी बना दिया गया। शपथ लेते समय उनके कुरते का साइज, आम कुरते की तरह ही था, लेकिन गन्ना विभाग का मुंशी बनते ही लम्बा होता गया। और अब, जबकि पिछले महीने वीर बहादुर की कृपा से उन्हें मोटी और बस वाला वह बेबस विभाग भी मिल गया जो किसी समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार राजकुमार संजय सिंह के पास था, तो अपने मुंशीजी का कुरता घुटने से नीचे तक आ गया।

वीर बहादुर कहते हैं, "मुंशी बहुत प्यारा आदमी है। निहायत ईमानदार है। इसीलिए मैं उसे बहुत चाहता हूं। दूसरे मंत्रियों की तरह वह मीन-मेख नहीं निकालता है।" मुंशी भी कहते हैं, "मुख्यमंत्रीजी तो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। दूसरे लोग हर चौथे-पांचवें दिन गणेश परिक्रमा करने हाईकमान के पास भाग जाते हैं, लेकिन आज तक मैं एक बार भी दिल्ली नहीं गया। क्यों जाऊं हाईकमान की परिक्रमा करने। मैं तो लखनऊ में ही अपने 'तीर कमान' की परिक्रमा कर लेता हूं।"

ज्यों-ज्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों मुंशीजी के कुरते की लम्बान भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब कुरता पांव को छूने लगा है। सुबह बिस्तर से उठते ही वह कुरता पहनते हैं, और झट अपने देवता यानी 'तीर कमान' के चरण स्पर्श करने कालिदास मार्ग पहुंच जाते हैं। 'तीर कमान' के दूसरे दरबारी मुंशीजी को देखते ही आपस में शर्त लगाने लगते हैं, "अच्छा बताओ आज मुंशीजी के कुरते के नीचे धोती है या पाजामा ?"

एक दिन जब ऐसी ही शर्त लग रही थी, तो एक दरबारी प्रमोद बोल उठा, "मैं शर्त लगाता हूं, एक पर दस दूंगा, आज मुंशीजी के कुरते के नीचे न धोती है न पाजामा।"

गोपी, श्याम और राम औतार दग रह गये। लेकिन तभी राम औतार को मजाक सूझा, "अच्छा प्रमोद, यह बताओ तुम्हें कैसे मालूम कि मुंशीजी के कुरते के नीचे कुछ नहीं है ?"

"धत् पंडित, भले ही तुम यूनिवर्सिटी के प्रसीडेंट रह चुके हो, लेकिन लंठई की तुम्हारी आदत नहीं जायेगी। तुम्हें दिखायी नहीं पड़ रहा है कि आज मुंशीजी का कुरता ऊपर से नीचे तक सपाट है। कल ही तो अपने 'तीर कमान' ने मुंशीजी से कहा था कि तुम लंगोट पहना करो, लेकिन तुम्हारा लंगोट तुमसे पहले वाले मंत्री के लंगोट से मजबूत होना चाहिए। मुंशीजी ने भी सोचा जब लंगोट से ही काम चल जायेगा, तो धोती-पाजामे का खर्च ही क्यों न बचा लिया जाये। यही वजह है कि आज मुंशीजी के कुरते के नीचे न धोती है न पाजामा।" प्रमोद की बात सुनते ही जोरदार ठहाका लगा।

'तीर कमान' जब हाईकमान के पास होते हैं या फिर वैष्णो देवी, गंगोत्री या विंध्याचल के दर्शन के लिए गये होते हैं, तो मुंशीजी ही 'तीर कमान' की तरफ से जनता से मिलते हैं। कालिदास मार्ग वाले बंगले में बरसों से लगे शामियाने के नीचे और बाहर सैकड़ों की तादात में मुख्यमंत्री के दर्शन के लिए आयी जनता जब तीर कमान की अनुपस्थिति में मुंशीजी से मिलती है, तो मुंशीजी की मिलनसारिता का जवाब नहीं रहता। इसी शनिवार को जब दर्शनार्थियों की भीड़ में मुंशीजी घुसे, तब कमजोर आंखवाला एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला, "मुख्यमंत्री गोण्डा से छठी बार आ रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ।"

सहमी हुई भीड़ में मुंशीजी चिल्लाकर कहते हैं, "मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुंशी हूं, मुंशी।" तभी एक दूसरा फरियादी बोला, "अरे मुंशी हों या मुख्यमंत्री, हमें तो काम से मतलब।"

"होगा-होगा, बिलकुल होगा। भगवान पर भरोसा रखो, सबका काम होगा।" मुंशीजी फिर चिल्लाये। तभी भीड़ से दूर खड़े दरबारी गोपी ने ऊंची आवाज में पूछा, "अरे मुंशी, कौन से भगवान, तुम्हारे या सबके।"

तेज आंखों से मुंशीजी गोपी को घूरते हैं। फिर चश्मे को नाक तक लाकर बुदबुदाते हैं, "भले ही मुझसे सीनियर हो तो क्या हुआ। तुम्हारे पास 'होम' है, तो भगवान की कृपा से मेरे पास 'वाइन,' 'केन' और 'बस' है। किसी दिन 'वाइन' पिलाकर जब 'केन' लेकर दौड़ाऊंगा, तो किसी बस में ही चढ़ोगे। अभी तो पुराने मंत्री वाली ही बसें और ड्राइवर हैं। ड्राइवर तुम्हें बस पर बिठाकर उन्नाव के आगे गंगा में ही कुदायेगा, क्योंकि उस पर भी हमारी ही 'वाइन' चढ़ी होगी। तुम जैसे दरबारी ही तो हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हैं। कहीं सांप छुड़वाते हो, तो कहीं लाठी चलवाते हो।" मुंशीजी बुदबुदाते हुए आम जनता की दरख्वास्तें इकट्ठा करने लगे। तभी गाजीपुर से आया एक टुटपुंजिया नेता बोला, "बधाई हो, मुख्यमंत्री के मुंशीजी को।"

"काहे की बधाई, मैं तो मुख्यमंत्रीजी का सेवक हूं। उनकी ही दया है, जो अफसर मेरी शिकायत करता है, भगवान उसे हटा देते हैं। दारू कमिश्नर ने शरारत की, हटा दिया गया। जब बस विभाग में आया, तो फिर मेरे 'अण्डर' में हो गया। अब गिड़गिड़ा रहा, माफ कर दीजिए। गन्ना सचिव ने 'मुखबिरी' करनी शुरू की, तो उसका भी पत्ता कट गया। मैं तो आस्तिक हूं, भगवान पर विश्वास करता हूं। इसी कारण काजल की कोठरी में रहते हुए भी कुरता बिलकुल शफ्फाफ है। दारू विभाग में तो मैंने इस बार सारे ट्रांसफर की रोक दिये।"

मुंशीजी के अनेक रूपों को देखकर 'तीर कमान' के सखा बलराम ने उनके कान में एक दिन फुसफुसाकर कहा, "मेरी एक बात गांठ बांधे रहना, अपने इस मुंशी को कभी भूलकर भी हाईकमान के आगे न करना। अगर किसी दिन उनकी नजर उस मुंशी पर पड़ गयी, तो समझो तुम्हारा पत्ता साफ हो जायेगा।"

"वह कैसे, क्यों ?" आश्चर्य भरे 'तीर कमान' ने पूछा।

"वह ऐसे कि अभी तक तुम्हारे जिन 'गुणों' के कारण हाईकमान तुम्हें गले में लटकाये हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा 'गुण' इस मुंशी में हैं। इसलिए ऐ मेरे दोस्त, तू कभी इस मुंशी को हाईकमान के आगे न करना।"

—भेदिया

छाया : एस०पी० प्रेमी

जीवन के रंग अजीब...

शुक्र है बोरोलीन करीब

सुगन्धित ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

BOROLINE
REGD TRADE MARK
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM

सूखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

GD

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नही

जी डी फार्मास्युटिकल्स
कलकत्ता ७०००५३

Response1030

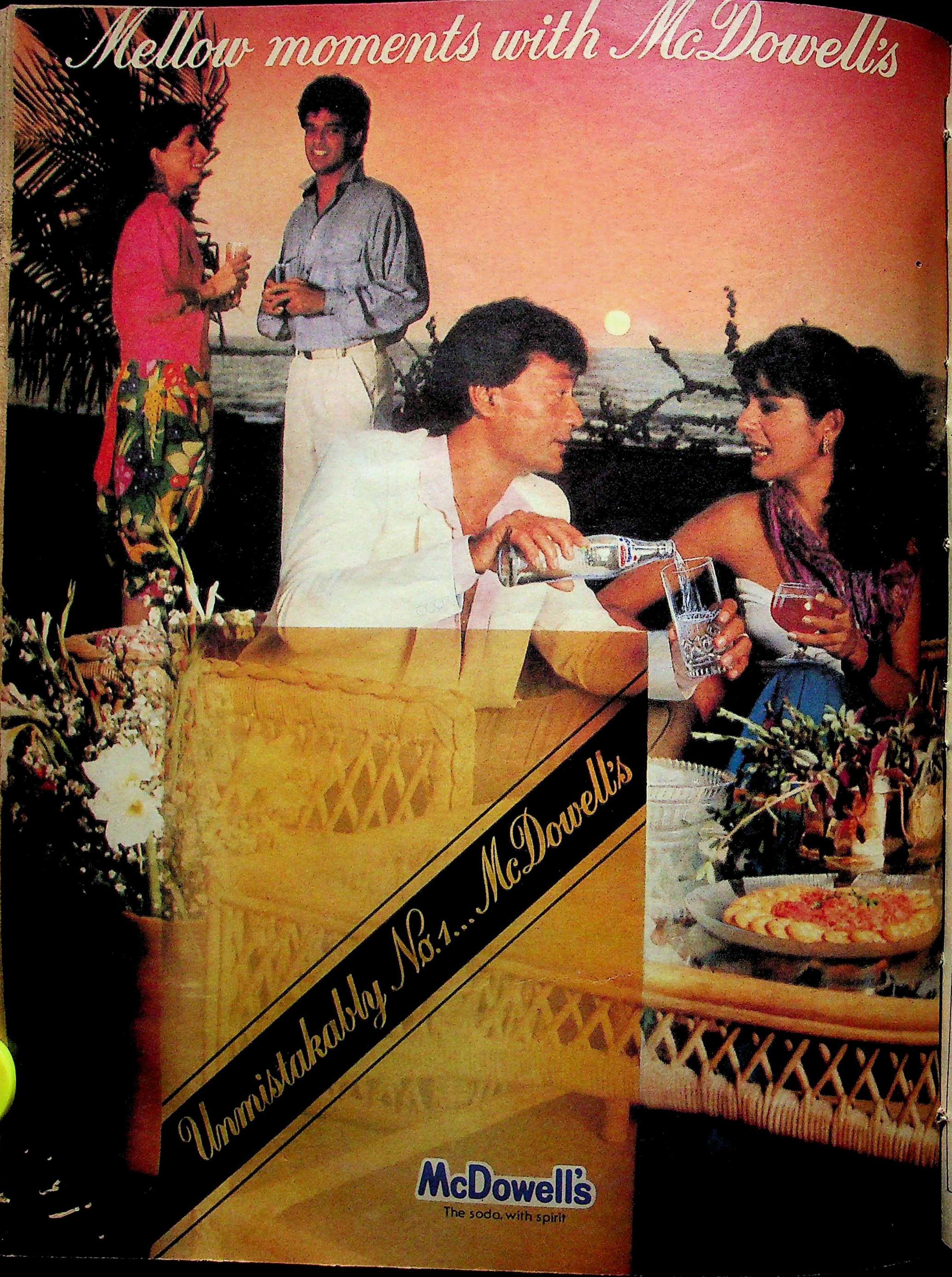
Mellow moments with McDowell's
Unmistakably No.1... McDowell's
McDowell's
The soda, with spirit

महा ठग नटवरलाल

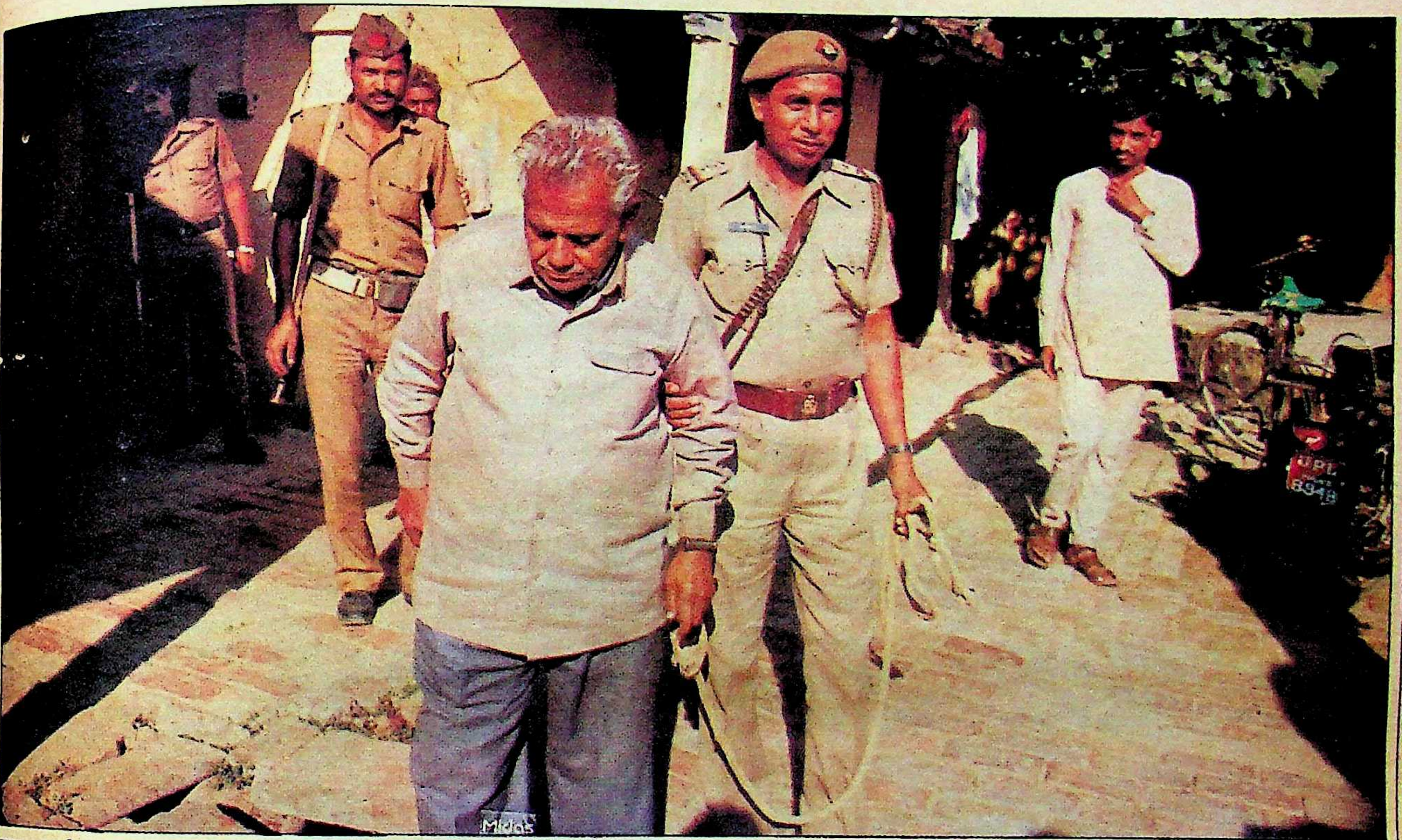

पश्चाताप के बजाय गर्व : नटवर लाल

पिछली आधी शताब्दी से नटवर लाल ने तरह-तरह से लोगों को ठगा है और पुलिस की आंखों में बार-बार धूल झोंकी है। पिछले दिनों वह एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ठगी का पर्याय बने ७३ वर्षीय नटवर लाल ने अब तक किस प्रकार से लोगों को ठगा है और आगे उसके क्या इरादे हैं?

"**क्या** आप अपनी ठगी का कोई करिश्मा दिखा सकते हैं?" बनारस के कैंट थाने में मौजूद आला पुलिस अधिकारी हथकड़ीबंद एक वृद्ध आदमी से कौतूहलवश यह सवाल कर रहे थे। नाटे कद और भारी-भरकम शरीरवाला वह वृद्ध हलके से मुस्कराया और बोला, "आप देखना चाहते हैं मेरा करिश्मा, तो सादी वर्दी में मेरे पीछे अपने दो आदमी लगा दीजिये। फिर बताइये किस सेठ या व्यापारी या नगर के रईस से कितने लाख रुपए लाने हैं।" जवाब देनेवाला वह बुर्जुग था—अंतरराष्ट्रीय स्तर का मशहूर ठग ७३ वर्षीय नटवर लाल, जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस और गुप्तचर संस्थाओं में अपनी कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता का सिक्का जमानेवाली बंबई पुलिस की ही नहीं, 'इंटरपोल' (अंतरराष्ट्रीय पुलिस) तक की आखों में भी अनेक बार धूल झोंक चुका है।

पिछले ५० वर्षों से भी अधिक वक्त से देशभर में एक-से-एक ठगी के रोमांचक कारनामे करनेवाला नटवरलाल एक 'मिथ' बन चुका है। अब कहीं भी कोई धोखाधड़ी या चालबाजी करता है, तो बस छूटते ही लोग कहते हैं, " अरे भाई यह तो नटवरलाल है।"

नवंबर के प्रथम सप्ताह में यही नटवरलाल जब गोरखपुर में एक घड़ी के व्यवसायी के यहां लाखों की घड़ी ठगने के चक्कर में पकड़ा गया, तो पुलिस को भी पता नहीं चला कि उसकी गिरफ्त में फंसा यह आदमी नटवरलाल है। फिर उसे बनारस शहर के कैंट थाने में लाकर बंद कर दिया गया। कैंट थाने के इंसपेक्टर रामदेव शुक्ल कहते हैं कि कई दिनों तक तो उसने गलत-सलत नाम और पते बताये। फिर एक सुबह उसने कहा कि शाम को मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना दूंगा। फिर शाम को जब उसने कहा कि मैं नटवर लाल हूं, तो मेरी सांस ही

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है"

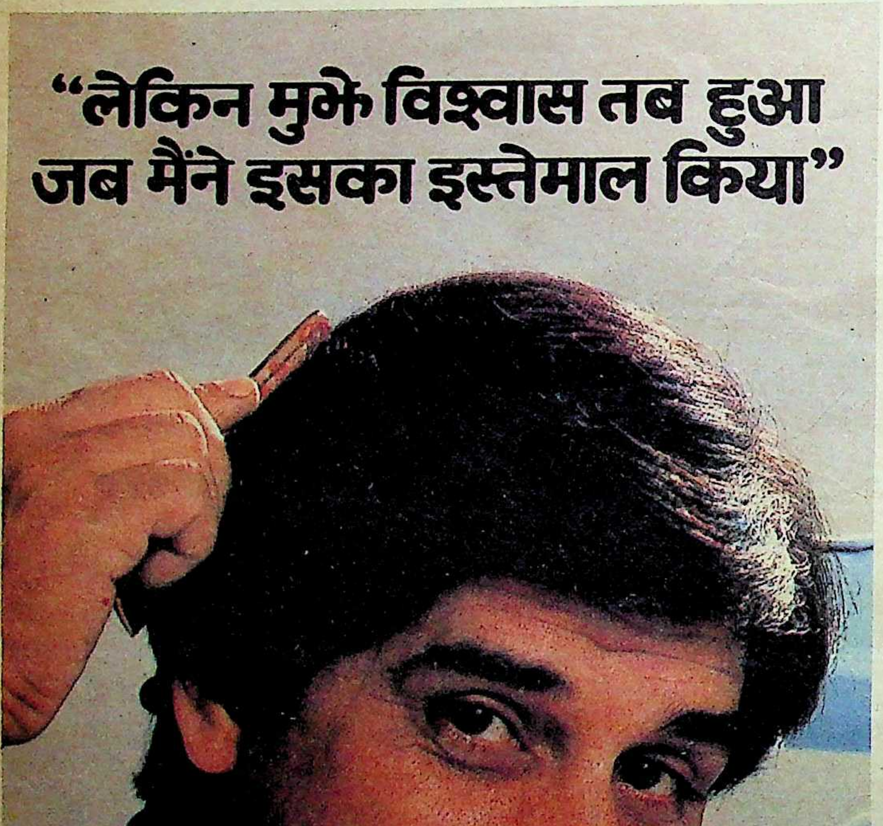

"लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रुसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए. गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश :

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Keo-Karpin
HAIR VITALIZER

बालों का झड़ना रोकने का **प्रमाणित** वैज्ञानिक तरीका।

*यह श्रृंगार सामग्री नहीं है।

Dey's® की संभाल, आपका भरोसा

DMHV-3

अटक गयी। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा देशप्रसिद्ध ठग मेरे सामने खड़ा है। तत्काल, बिहार पुलिस को सूचना भेजी गयी। बिहार सी०आई०डी० के अधिकारी तत्काल नटवर लाल की तमाम तस्वीरें लेकर पहुंचे और इस बात की पुष्टि की कि सचमुच यही नटवर लाल है।

नटवर लाल के संग इलाहाबाद के तीन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई जिनमें जीरो रोड के एक प्रेस का मालिक, एक घड़ी-व्यापारी और इलाहाबाद में ही पान मसाले का एक व्यवसायी है। बताया जाता है कि प्रेस मालिक नटवरलाल के सम्पर्क में लगभग एक साल पहले आया था। एम०पी० श्रीवास्तव बनकर नटवर लाल प्रेस में एक दिन अपना लेटर पैड छपाने पहुंचे और छपाई का जब दोगुना पैसा दिया तो प्रेस-मालिक बेहद खुश हुआ। धीरे-धीरे प्रेस मालिक उनका भक्त हो गया और नटवर लाल जाली बैंक ड्राफ्टों की छपाई उसके प्रेस में करवाने लगे। यह भी बताया जाता है कि प्रेस मालिक के माध्यम से ही नटवरलाल पानमसाले के व्यवसायी के सम्पर्क में आये। पान-मसाले के व्यवसायी से नटवरलाल ने अपना परिचय दिया कि वह एच०एम०टी० घड़ियों का विदेश में एक्सपोर्ट करता है। इसलिए वह बेहद सस्ते दामों पर एच०एम०टी० घड़ियां दिलवा सकता है। अगर वह इसके बिकवाने का इंतजाम करे, तो उसे अच्छा कमीशन दिया जायेगा। पानमसाले के व्यवसायी को लालच आ गया और उसने जानसनगंज स्थित एक घड़ी-दुकानदार से नटवरलाल को मिलवाया। घड़ी-दुकानदार ने नटवरलाल से डेढ़-दो सौ घड़ियां खरीदीं और ५०,००० रुपए का भुगतान किया। इसके बाद ऐसा ही चक्कर जब वह गोरखपुर की 'वाच कंपनी' में चला रहा था कि पकड़ा गया।

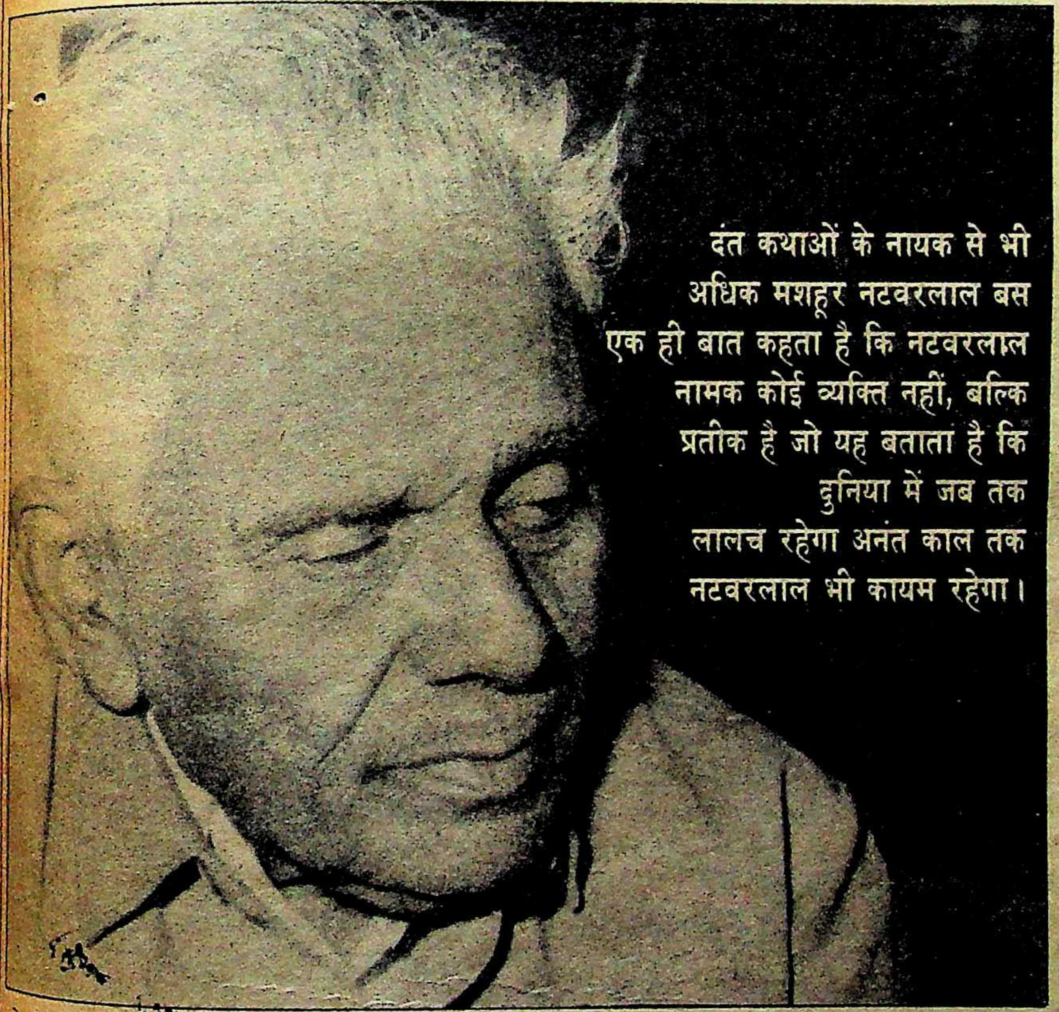

दंत कथाओं के नायक से भी अधिक मशहूर नटवरलाल बस एक ही बात कहता है कि नटवरलाल नामक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रतीक है जो यह बताता है कि दुनिया में जब तक लालच रहेगा अनंत काल तक नटवरलाल भी कायम रहेगा।

पर नटवरलाल के लिए यह महज मामूली ठगी थी। जब कभी वह पकड़ा भी गया, तो कुछ ही दिनों में जेल अधिकारियों को उल्लू बनाकर भाग निकला। २८ जून, १९८० को जब नटवरलाल बंबई जेल से भागा, तो बंबई पुलिस को सांप सूंघ गया। दरअसल, नटवरलाल इंदौर जेल में १४ वर्ष का सश्रम कारावास भोग रहा था, इसी बीच बंबई में उसके द्वारा की गयी ठगी के मामले में इसे बंबई के अर्थर रोड जेल में ले जाया गया। १९७७ में भी वह एकबार बंबई पुलिस को चकमा दे चुका था, इसलिए पुलिस जरूरत से ज्यादा सतर्क थी। बंबई में अचानक उसने बीमारी का नाटक किया। उसे कड़े पहरे में अस्पताल में भरती करवाया गया। अस्पताल में रहने के दौरान उसने वहां पहरा दे रहे सिपाहियों को यह कहकर पटाया कि वह अपना इलाज बेहतर ढंग से करवाना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए उसका एक मित्र जो 'ताज होटल' में ठहरा है उससे मिलकर वह कुछ कर्ज लेना चाहता है। कांस्टेबुल नटवरलाल के झांसे में आकर उसे 'ताज होटल' ले गया। पर वहां नटवर का कोई मित्र होता तब न मिलता। नटवरलाल पलक झपकते 'ताज होटल' से चंपत हो गया और बंबई पुलिस फिर एक बार हाथ मल कर रह गयी।

एक दिन कर्नाटक बंदर स्थित रेलवे गोदाम के सुप्रिटेंडेंट के पास लक्ष्मीनारायण अग्रवाल नामक एक आदमी पहुंचा। उसने सुप्रिटेंडेंट को यह कहते हुए रेलवे की आर०आर० रसीद दी कि उसका २३५ बोरा खांडसारी शक्कर मुजफ्फरनगर से यहां आया है। कृपया, उसे मेरे हवाले कर दें। आर०आर० रसीद बिलकुल सही थी। लिहाजा, गोदाम के सुप्रिटेंडेंट ने ८३,००० रुपए के खांडसारी शक्कर लक्ष्मीनारायण अग्रवाल नामक उस व्यक्ति को सौंप दिया। थोड़ी देर बाद जब वैसी ही रसीद लेकर उस माल के असली दावेदार पहुंचे, तो गोदाम के सुप्रिटेंडेंट ने सिर पीट लिया। वह लक्ष्मीनारायण अग्रवाल और कोई नहीं, नटवरलाल ही था। इस वारदात के ठीक पांच माह बाद जब कानपुर जंक्शन पर एम०एल० गुप्ता नामक एक सज्जन ऐसी ही हेराफेरी करने की कोशिश करते पाये गये, तो पुलिस अधिकारी को शंक हुआ। पहले तो एम०एल० गुप्ता नामक ये सज्जन काफी आनाकानी करते रहे। पर जब उनकी खानातलाशी ली गयी, तो कई जाली रसीद और बैंक ड्राफ्ट तथा लेटर पैड मिले। बाद में उन सज्जन ने कबूल किया कि वह एम०एल० गुप्ता नहीं, नटवरलाल हैं। कानपुर में नटवरलाल पर केस चला और सजा भी हुई, पर वहां से भी एक दिन अपना चक्कर चलाकर वह भाग निकला।

तीस वर्ष पूर्व नटवरलाल ने इंदौर के 'यूनाइटेड कमर्शियल बैंक' से साढ़े चार लाख रुपए की ठगी की थी। इसके लिए बैंक अधिकारियों को विश्वास में लेने के लिए पहले उसने एक लाख रुपए से अपना खाता खोला। बैंक अधिकारियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तो वह काफी प्रभावित कर ही चुका था। फिर बाद में एक दिन उस बैंक में नकली हुंडी और रेलवे रसीद दिखाकर नटवरलाल ने साढ़े चार लाख की ठगी कर ली।

यह घटना १ जुलाई, १९८६ की है। लखनऊ के चौक स्थित खुनखुनजी रोड में एक मशहूर आभूषणालय 'मेसर्स गुलाबराय गोविंद प्रसाद ज्वेलर्स' में सभ्य सा दीखनेवाला एक बुजुर्ग आदमी एक दिन गाड़ी से पहुंचा। उसने परिचय दिया कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप्त सचिव एस०एस० शरण है और उसे कुछ गहने खरीदने हैं। ४५,००० रुपए का जेवर उसने पसंद किया और बोला अगले दिन सचिवालय के गेट नंबर एक पर वह ये गहने पहुंचा जाये और ४५,००० के ड्राफ्ट ले जाये। आभूषणालय के मालिक हरिश्चन्द्र अग्रवाल ने 'माया' को बताया कि उन्होंने अपने एक कर्मचारी कृष्णजीवन रस्तोगी के हाथ गाड़ी से उन गहनों को सचिवालय के गेट पर भेजा। सचमुच एक चमचमाती नयी गाड़ी पर मुख्यमंत्री के तथाकथित आप्त सचिव एस०एस० शरण प्रतीक्षारत बैठे थे। कृष्णजीवन रस्तोगी ने गहने का वह डिब्बा उन्हें दिया और ४५,००० का बैंक ड्राफ्ट ले लिया। शक का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। भला मुख्यमंत्री का आप्त सचिव जालसाजी कर सकता है। पर, जब

साक्षात्कार/नटवरलाल

'लोभी दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता'

माया:पिछले पचास सालों से आप ठगी के लिए भारत में मशहूर रहे हैं, कुछ इस तरह कि आपका नाम ही एक 'मिथ' बनकर रह गया है। क्या आप इस धंधे को अपराध नहीं मानते?

नटवरलाल: देखिये ठगी एक विद्या है, एक विशिष्ट कला! यह कहीं से अपराध नहीं दिमागी करिश्मा है। ठगी के इतिहास को देखिये तो यह विद्या भारत में आदिकाल से रही है। अंग्रेजों को यहां आने पर बहुत बाद में इसका पता चला। मेरा सिद्धांत है कि मैं बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों और उन बड़े व्यापारियों को चूना लगाता हूं, जो आम निरीह और गरीब लोगों को खुलेआम ठगते हैं। पूंजीपति जो भी होगा मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह ठग होगा। पूंजीपति कभी ईमानदार हो ही नहीं सकते। सब ठग हैं। बगैर ठगी किये कोई अमीर नहीं बन सकता। महज जीवन-यापन करने के लिए थोड़े से ही पैसों की जरूरत होती है। इसलिए जीने की आवश्यकता से अधिक अगर कोई धन अर्जित करता है, तो निश्चित रूप से वह ठग है। मजदूर, किसान जी तोड़ मेहनत के बावजूद दो जून की रोटी ठीक से नहीं जुटा पाते। अपने देश में मेहनतकशों और गरीबों की ही दुर्गति है और जो अमीर इन गरीबों की दुर्गति करते हैं, मैं उन्हें ही तो तबाह करता हूं। इसलिए समाज में इज्जत से रह रहे खुले आम जनता को ठगनेवालों को मैं ठगता हूं। ईश्वर ने मुझे ऐसे हीं लोगों को ठगने के लिए पैदा किया है। इतिहास की किताबों में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से आपने पढ़े होंगे कि कैसे वह अमीरों को चूना लगाता था। पर क्या वह ठग कहा जायेगा? वह समाज और अपने देश का खिदमतगार था। मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करता हूं।

माया: क्या ईश्वर और समाज आपकी इन सफाइयों के बावजूद आपको माफ करेगा?

नटवरलाल: समाज क्या सोचता है, मैं नहीं कह सकता, पर ईश्वर मुझ पर खुश होंगे इतना मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं रुपए के कीड़ों का गला दबाता हूं। कानून, विधान, पुलिस मैन्युअल, आई०पी०सी०, सी०आर०पी०सी० ये जितनी चीजें हैं यह सब हम-आप अपनी सुविधा से बनाते बिगाड़ते हैं। जरूरत पड़ने पर संविधान में भी संशोधन किया गया है। इसलिए कानून या संविधान बड़े लोगों के मतलब और जरूरत के हिसाब से संशोधित होता रहता है। नियम शिथिल किये जाते हैं। पर ईश्वर का कानून सबसे अव्वल है जिसे न तो खत्म कर सकते हैं, न संशोधित कर सकते हैं। ईश्वर का ही नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है, तो क्या बड़ी मछली पाप करती है। इसलिए, मैं ठग हूं यह ईश्वर की प्रेरणा है। अभी मैं पकड़ा गया इसके पीछे भी शायद ईश्वर की ही कोई योजना हो। इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस धरती की पुलिस में यह कूवत नहीं कि नटवरलाल को पकड़ ले। ईश्वर ने चाहा, तो मैं पकड़ा गया।

माया: आपने इस बार अपना असली नाम क्यों बता दिया? आप बच भी तो सकते थे?

नटवरलाल: हां, बड़ी आसानी से बच सकता था। मुझे लगा कि इधर कई वर्षों से नटवरलाल का नाम सुर्खियों में नहीं आया है, इसलिए लोग कहीं अपने प्यारे नटवरलाल को भुला न दें। लिहाज़ा, दिल ने कहा नटवरलाल अपना नाम बता ही दो।

माया: आपके जीवन की सबसे पहली ठगी कौन सी थी?

नटवरलाल: सबसे पहली ठगी कलकत्ते में की थी। आजादी के पहले की बात है। कलकत्ते में एक सेठ के बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैं घर से कलकत्ता गया था कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुझे आई०काम० की परीक्षा देनी थी। परीक्षा फीस भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास। सो उस सेठ से मैंने साठ रुपए मांगे, इस अनुरोध के साथ कि ट्यूशन-फीस के पैसों में से वह धीरे-धीरे काट लेंगे। पर सेठ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह अगर मैं रुपए बांटता चलूं, तो कंगाल ही हो जाऊंगा। मैंने उसी दिन मन में ठान लिया कि सेठ तुमको कंगाल तो कर ही देंगे। बहरहाल, कलकत्ता में बिहार के काफी रिक्शा चलाने वाले और ठेलेवाले रहते हैं। उन सबों ने मेरे लिए साठ रुपए का चंदा कर बंदोबस्त कर दिया। परीक्षा देकर मैं फिर उस सेठ के पास गया और उसके बच्चों को पढ़ाने लगा। सेठ को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा तो थी ही। उन दिनों कपड़े का बाजार बड़ा गर्म था। कपड़ों की कीमत अचानक काफी बढ़ गयी थी। एक सुबह मैं सेठ के पास गया और कहा कि बंबई से कपड़े के व्यवसाय का एक दलाल आया है। वह बेहद रियायत में कपड़े दिलवा सकता है, जिसे बेचकर आप रातों-रात करोड़ों रुपए बटोर सकते हैं। सचमुच लोभी दुनिया में ठग को कभी उपवास नहीं करना पड़ता। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने कहा मुझे उस आदमी से जल्दी मिलवाओ, पर वह आदमी होता तब न मैं उसे मिलवाता। लिहाजा, अगले दिन मैंने सेठ से कहा कि व्यवसाय के चक्कर में वह बंबई लौट गया है। वह अपना बंबई का पता दे गया है कि धंधे की बात हम वहीं आकर करें। बस सेठ ने दो लाख की थैली अपने मुनीम के हाथ देकर मेरे साथ कर दिया और बंबई में अन्य खर्च के लिए पांच हजार रुपए अलग से दिये। सेठ के मुनीम को लेकर मैं बंबई गया। बंबई जाकर हम दोनों 'माधव आश्रम' होटल में ठहरे। मुनीम को होटल में ही रुकने को कहकर मैं बंबई की एक कपड़ा मिल में गया। वहां मिल के सभी रास्ते का मुआयना किया और होटल चला आया। फिर मुनीम से कहा चलो रुपए उठाओ और एजेंट से सौदा तय करवाते हैं। वह रुपया सेठ की 'ब्लैकमनी' था और उन दिनों धरपकड़ काफी तेज थी, सो इतने रुपयों के साथ जाने में मुनीम भयभीत था। उससे वह थैली मैंने अपने हाथ में ली और कपड़ा

मिल के अंदर गया तथा चुपचाप दूसरे रास्ते से निकल गया। मुनीम बस हाथ मलकर रह गया। फिर वहां से मैं सीधे वी०टी० स्टेशन आया और ट्रेन पकड़कर सीधे अपने गांव पहुंचा। पैसे घरवालों को दे दिये। उन पैसों से कुछ जमीन खरीदी गयी। फिर कुछ दिन बाद कलकत्ता चला आया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक जारी है और शायद मरते दम तक जारी रहेगा।

माया: ठगी से हासिल रुपयों का क्या करते रहे?

नटवरलाल: देखिए, इस तरह के पैसे कभी ठहर नहीं सकते। इसलिए गरीब छात्रों, महिलाओं और जरूरतमंदों के बीच तत्काल मैं उन पैसों को बांट दिया करता हूं। कई छात्रों को नियमित रूप से मैं पढ़ाई के खर्चे देता रहा हूं और कितनों की लड़की की शादी में मदद की। पर जिन लोगों की मैंने आर्थिक मदद की उन्हें भी यह पता नहीं चलने दिया कि यह आदमी जो पैसे मुझे दे रहा है वह नटवरलाल है। धर्म स्थलों पर भी अपने जीवन में लाखों रुपए मैंने दान दिये। मसलन, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और देवघर आदि के मंदिरों में। मैं जब इन मंदिरों के पंडे-पुजारियों को दान में मोटी रकम देता था, तो वे सब पूछते सेठ अपना नाम तो बताते जाओ। दान तुम्हारे नाम पर चढ़ जायेगा। मैं बस इतना कहकर उन सबों से पीछा छुड़ाता कि मैं कहां का सेठ हूं और मेरा क्या नाम है, यह सब छोड़ो। मेरे पास बहुत पैसा है। बस मंदिर के कल्याण के लिए मेरा गुप्तदान रख लो।

माया: क्या आपकी पत्नी और बच्चों ने यह धंधा छोड़कर चैन की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं कहा?

नटवरलाल: मेरी पत्नी और बेटे ने मुझे सचमुच बार-बार मना किया कि मैं इज्जत से जैसे दुनिया चलती है, पारिवारिक जीवन व्यतीत करूं। पर नटवरलाल घर बैठकर आटे-दाल का हिसाब जोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ था। यों कई बार मन में बात आयी कि यह धंधा छोड़ दूं, पर धीरे-धीरे लगा यह अब सिर्फ जरूरत नहीं आदत-सी बन गई है और अब मरने के साथ ही छूटेगी।

माया: आपके नाम पर एक फिल्म भी बनी है 'मि० नटवरलाल' क्या वह फिल्म आपने देखी?

नटवरलाल: *उस फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने मेरे नाम को व्यावसायिक रूप से सिनेमा हालों में भुनाया। मैंने उसे सूचना भिजवायी कि मुझे इसके एवज में रुपए मिलने चाहिए। उससे मुझे तीन लाख रुपए मिले।*

माया: क्या इस बीच कभी आप अपने गांव गये?

नटवरलाल: अभी इसी दीवाली में मैं सीवान में ही था। सिवान के 'शांति होटल' में ठहरा था। तबियत हुई कि एक टैक्सी लेकर गांव चला जाऊं और अपने पुराने मित्रों से मिलूं पर कुछ विशेष योजना सामने थी, सो नहीं जा सका। गांव में सब मुझे दिलोजान से चाहते हैं।

माया: आपके परिवार में अब कौन-कौन हैं?

नटवरलाल: मेरे परिवार में अब कोई नहीं। बस एक लड़का था मेरा जो एक साल पहले दुनिया से चल बसा। वह पटना विश्वविद्यालय का एम०ए० था। पत्नी लल्ली देवी अभी तीन-चार माह पहले गुजर गयी। मैं बहुत दुखी हूं, बस किसी तरह जी रहा हूं। मुझे एक बात का अफसोस मरते दम तक रहेगा कि अपनी पत्नी या बेटे के लिए मैं कभी कुछ नहीं कर सका। मेरी पत्नी ने पूरी जिंदगी अपने मायके (सारण जिले के तहत हथौड़ी गांव में) में व्यतीत की। पुश्तैनी गांव रूइया बंगरा (बिहार के सीवान जिले में) में मेरा घर तक सलामत नहीं। अब जबकि मेरी पत्नी व लड़का इस दुनिया में नहीं हैं, मैं जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका हूं।

माया: तब आप यह धंधा छोड़ क्यों नहीं देते?

नटवरलाल: आखिर मेरी सांस तो चल रही है। फिर नटवरलाल जब तक दुनिया में है, कुछ-न-कुछ होता रहना चाहिए।

माया: राजनीतिज्ञों से कभी आपका संपर्क हुआ?

नटवरलाल: अनगिनत नेताओं से मसलन, गुलजारी लाल नंदा, कर्पूरी ठाकुर, जार्ज फर्नांडीज। कितनों का नाम बताऊं। जेल में रहने के दौरान इन सबों से मुलाकात हुई। मेरे विचार से ये लोग कभी सहमत नहीं हुए। मैं इन नेताओं से कहता था कि पार्टी-वार्टी का चक्कर छोड़ो और सच्चे मन से समाज का हित करो।

माया: क्या राजनीति में आने का ख्याल कभी नहीं आया?

नटवरलाल: अजी तौबा कीजिये। मैं सीधे राजनीति में तो नहीं हूं पर जरा गौर से देखिए तो आज के नेताओं से ज्यादा अच्छा काम मैं कर रहा हूं।

माया: भारतीय पुलिस के बारे में आपकी क्या धारणा है?

नटवरलाल: भ्रष्ट और निकम्मी। समाज में अपराध बढ़ने का एक कारण पुलिस भी है।

माया: राजीव गांधी के बारे में क्या विचार हैं आपके?

नटवरलाल: वह कुछ पुराने नेताओं के हाथ के सुंदर खिलौने हैं। राजनीति उनकी समझ से बाहर की चीज है। नतीजा जो होगा बस देखते जाइये।

—विकास कुमार झा

आभूषणालयवाले ने बैंक ड्राफ्ट को कैश कराने भेजा तो पाया गया कि ड्राफ्ट जाली है। आभूषणालय के मालिक हरिश्चन्द्र अग्रवाल कहते हैं, "हम तो सिर पीट कर रह गये। पर कर ही क्या सकते थे?"

ठीक इसी तरह दिल्ली के पार्लियामेण्ट स्ट्रीट स्थित 'सुरेन्द्र वाच कंपनी' के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग सज्जन निकलकर दूकान में आये और कहा कि वह केन्द्रीय मंत्री नारायण दत्त तिवारी के आप्त सचिव डी०एस० तिवारी हैं उन्हें एकमुश्त कुछ घड़ियां खरीदनी हैं। फिर बत्तीस हजार की घड़ी लेकर जो नटवरलाल चंपत हुए, तो बाद में पता चला कि वह डी०एस० तिवारी नहीं, श्री ४२० नटवरलाल थे।

नटवरलाल से पाला पड़े यह कोई नहीं चाहता, क्योंकि कोई नटवरलाल की विद्या का शिकार नहीं होना चाहता। पर अनजाने में नटवरलाल की मुलाकात जिस किसी से भी हो गयी, वे लोग कभी नटवरलाल को भूल नहीं सके हैं। एक ज्योतिष ज्ञाता सज्जन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे कि एक स्टेशन पर एक अधेड़ व्यक्ति आकर उनके सामने की सीट पर बैठ गया। अचानक उनकी निगाह सामनेवाले व्यक्ति की हथेली पर पड़ गयी, तो एकबारगी वह चौंक उठे। सामने बैठे उस आदमी से कहा, "माफ करें, आपसे मेरा कोई परिचय तो नहीं, पर एक बात कहने की धृष्टता कर रहा हूं कि आपके हाथ में जैसी रेखाएं हैं वैसी किसी बड़े जालसाज यानी नटवरलाल जैसे व्यक्ति के हाथ में ही हो सकती हैं। आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा होऊं।"

सामनेवाला आदमी मुस्कराया, "भाई, अभी तक कोई जालसाजी मैंने की तो नहीं है, आगे जो हो।" बात हंसी में आयी-गयी होकर रह गयी। लगभग तीन चार स्टेशन के बाद वह ज्योतिष ज्ञाता सज्जन उठकर बाथरूम गये और लौटकर आये, तो देखा कि वह आदमी गायब था और वहां एक पर्ची लाइटर से दबी हुई रखी थी। तत्काल उन्होंने पर्चे को उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, "बंधु, मैं आपके ज्योतिष ज्ञान का कायल हूं। मेरा नाम नटवरलाल ही है।" पढ़कर वह अवाक रह गये। अनायास ठगों के उस्ताद से ऐसी मुलाकात से उन्हें रोमांच हो आया। वह लाइटर आज भी उनके पास सुरक्षित है और वह कहते हैं कि नटवरलाल ने उन्हें तोहफा दिया।

बहरहाल, दंत कथाओं के नायक से भी अधिक मशहूर नटवरलाल बस एक ही बात कहता है कि नटवरलाल नामक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रतीक है जो यह बताता है कि दुनिया में जब तक लालच रहेगा अनंत काल तक नटवरलाल भी कायम रहेगा।

क्या आपने किसी को अपना शागिर्द बनाया है जो आपके बाद आपकी जगह ले सके? 'माया' के इस सवाल पर नटवरलाल हंसता है और कहता है, "हां, बनाया तो है, लेकिन नटवरलाल सब नहीं हो सकते।"

छाया: प्रभाकर **—विकास कुमार झा**

क्या कहते हैं, नटवर के बारे में उसके गांववाले!

नटवर लाल के रूप में कुख्यात मिथिलेश प्रसाद सीवान जिले के जीरादेई उपथाना अंतर्गत रूइया बंगरा गांव के स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद का पुत्र है। रूइया बंगरा सीवान से १३ किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम के कोने पर हैं। यह गांव देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई से दो किलोमीटर दक्षिण में है।

मिथिलेश उर्फ नटवरलाल की बंगरा गांव में अब एक धूर जमीन नहीं है। उसके मकान वाली लगभग दो कट्ठा जमीन है जिस पर कभी उसका मकान हुआ करता था। अब मकान का अता-पता तक नहीं है। दो भाइयों में बस लगभग दो कट्ठे घरारी (घर वाली जमीन) है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यों ही पड़ी है।

बांके बिहारी प्रसाद

मिथिलेश अपने गांव बंगरा के नेशनल स्कूल में तीसरी तक पढ़ा, उसके बाद जीरादेई में सातवीं तक, उसके बाद सीवान में नौवीं तक, आर०जी० एकेडमी सीवान में पढ़ाई के दौरान डेरा लेकर रहा करता था। नौवें वर्ग के बाद वह कलकत्ता चला गया। मिथिलेश को बचपन से जानने वाले और उससे स्कूल में एक-दो आगे-पीछे पढ़ने वालों में बांके बिहारी प्रसाद, सूर्य नारायण सहाय, महेश्वर प्रसाद, सूर्य देव प्रसाद और गोरख प्रसाद (पांचों बंगरा गांव के) हैं।

मिथिलेश की १९४३ में हथौरी गांव में शादी हुई थी। उसके ग्रामीण मित्र सूर्य नारायण सहाय करते हैं कि विवाह के पूर्व ही वह ठगी के धंधे में आ गया था, पर इतना 'कुख्यात' नहीं हुआ था। उसकी एक मात्र लड़की का विवाह सीवान जिले में ही हसुंआ गांव में हुआ है। यह विवाह हथौरी से हुआ था। पर, साक्षात्कार के दौरान नटवरलाल ने 'माया' को बताया कि उसके एक लड़का था जो एक साल पहले मर गया। लेकिन गांववाले इस बात को झूठ करार देते हुए कहते हैं कि नटवरलाल के बस एक लड़की है। दामाद रांची में राडार आपरेटर है।

मिथिलेश ने सर्वप्रथम बचपन में अपने चाचा मुक्ति प्रसाद की पत्नी के गहने गायब कर बेचे। उसने जोर-शोर से यह 'धंधा' १९३३ में शुरू किया। अपने गांव के पड़ोसी और स्कूल में साथ पढ़नेवाले सूर्य नारायण सहाय के जाली दस्तखत से चेक बनाकर दुकानदार को देकर उससे डेढ़ हजार पार्कर पेन खरीद लिये। उन दिनों सूर्य नारायण सहाय का परिवार कलकत्ता में ठीके पर मकान की रंगाई-पोताई का कार्य किया करता था। मिथिलेश ने दुकानदार को जो जाली चेक दिया, उसका एमाउन्ट अधिक था और सूर्य नारायण के एकाउन्ट में उतने पैसे नहीं थे, जिससे चेक पकड़ में आ गया, पर तब तक मिथिलेश फरार हो चुका था। उस डेढ़ हजार पार्कर पेन को उसने अपने बंगरा गांव में बांटा। ७६ वर्षीय सूर्य नारायण सहाय १९३४ से होमियोपैथी के चिकित्सक हैं। उन्होंने 'माया' को बताया, "आज से २५ साल पूर्व उसे देखा था जब उसे गांव में पुलिस 'वेरीफिकेशन' के लिए लेकर आयी थी।"

प्रारंभ में उसे उसके पिता ने ही रेलवे को जाली बिल्टी बनांने में उसका सहयोग किया।

उसके पिता तो बिल्टी बनाने का काम ही किया करते थे। उसने मुझे भी लूटा। अगर यह कहूं कि मेरे यहां से ही लूटने का धंधा प्रारंभ किया, तो गलत न होगा।

"मुझे घृणा होती है, उसका नाम सुनकर और दुख भी होता है कि बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, पर उसने अपना जीवन बरबाद कर लिया। गांव में कुर्की-जब्ती के समय सिर्फ उसका बाप गांव में था, पर उसके बाद चला गया फिर नहीं आया। अब तो उसका नाम ही सुनता हूं।"

मिथिलेश से दो दर्जे जूनियर स्कूल साथ जाने-आने वाले बांके बिहारी प्रसाद का कहना है, "एकस्ट्रा आर्डिनरी ब्रिलियेंट। गॉड गिफ्ट है उसे। बचपन से ही नकल करने में वह बहुत तेज था। ऐसी खूबसूरत नकल कि असल-नकल में फर्क करना मुश्किल।"

बांके बिहारी अवकाश प्राप्त जन संपर्क अधिकारी हैं। उन्होंने 'माया' से कहा, "वह हथियार नहीं छूता, ताला-तिजोरी नहीं तोड़ता, गरीबों को नहीं सताता। पूंजीपतियों को जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार का कानून है और जो करोड़ों लोगों को धोखा देकर लूट रहे हैं, उन्हीं को तो लूटता है, तो क्या गलत करता है।"

रूइया बंगरा के ही आर०के० मुरारी को कहना है, "हमारी और उसकी शादी १०-१५ दिनों के अंतराल में हुई। जहां मिथिलेश का विवाह हुआ वहां मेरा ननिहाल है। उसके ससुराल में उसका एक मात्र साला है जो वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर के एक हाई स्कूल में शिक्षक है। उसका भांजा आई०ए०एस० अफसर है। उसकी ससुराल काफी शिक्षित है।"

आर०के० मुरारी अवकाश प्राप्त हेड मास्टर हैं। उन्होंने कहा, "नटवर 'शार्प ब्रेन' का है। लैंग्वेज एक्सपर्ट। मूल निवासी की सी भाषा बोलता है। वह जब यहां गांव में था, तो हर पूर्णमासी को सत्यनारायण-भगवान की कथा कहवाता था और पूरे गांव को खिलाता था। उसने गांववालों की बहुत आर्थिक सहायता की थी। रांची में बहुतों की मदद की। राह चलते लोगों की भी मदद करता था। यह दूसरी बात है कि आज कोई यह स्वीकार करने वाला नहीं कि उसने मेरी आर्थिक मदद की। जब मैं पटना में पढ़ा करता था, तो जब कभी उसकी मुझसे भेंट हो जाती थी, तो मेरे साथ दस-बीस जितने मित्र रहते, सबको पिन्टू होटल में ले जाकर जबर्दस्ती खिलाया करता था।"

आर०के० मुरारी

सूर्यनारायण राय

आर०के० मुरारी मिथिलेश से पांच-छः वर्ष छोटे हैं। उन्होंने 'माया' से कहा, "उसके 'काम' पर शुरू में दुख होता था, पर जब देखा कि नीचे से ऊपर तक—देश का प्रधानमंत्री तक देश के साथ 'फ्रॉड' कर रहा है, तो नटवरलाल कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। वह अपने पास कुछ नहीं रखता, सब बांट देता है गरीबों में, जरूरतमंदों को।"

नटवरलाल के प्रति उसके गांव के अधिकांश लोगों के दिल में सम्मान है। पर पुलिस के भय से कोई सम्मान नहीं जताता या खुलकर कुछ नहीं बोलता। गांव वालों का कहना है कि उससे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर गांव के एक नवयुवक (नाम नहीं बताया) ने 'माया' से कहा, "जीरादेई का नेकनाम बाबू (राजेंद्र बाबू) के कारण हुआ और बंगरा बदनाम हुआ नटवर की वजह से।"

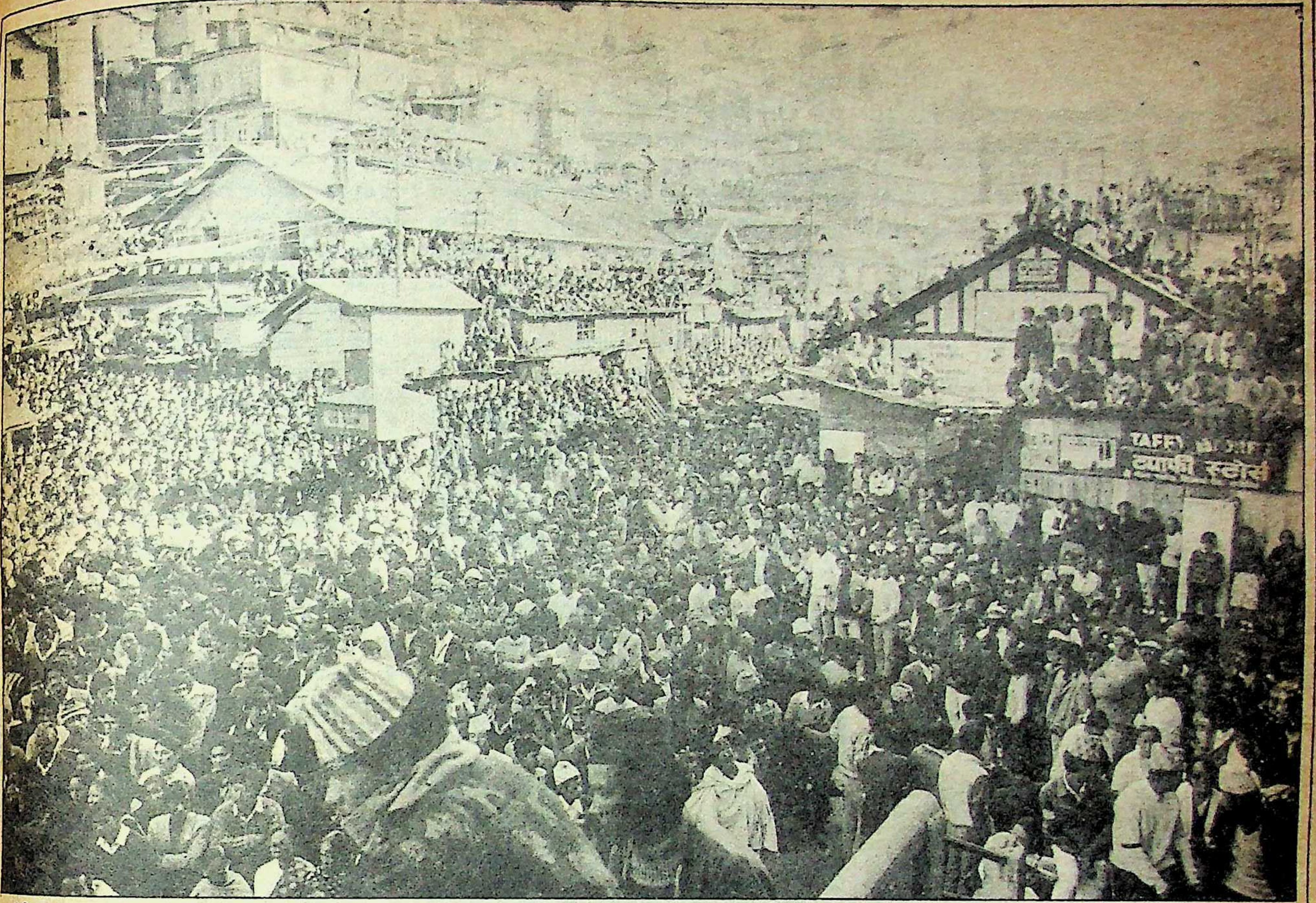

असंतोष की आग : दार्जिलिंग में गोरखालैण्ड मुक्ति मोर्चे की एक सभा

गोरखालैण्ड आंदोलन

क्या दार्जिलिंग में फिर खून बहेगा?

समझौते के जब भी आसार बनते हैं, सुवास घीसिंग नयी मांगें रखकर शांति की संभावनाओं को धूमिल कर देते हैं। क्या गोरखालैण्ड आंदोलन पर ऐसे लोग हावी होते जा रहे हैं जो उग्रवादी हैं और सुवास घीसिंग को अपने इशारे पर नचा रहे हैं? दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल' पर रजामंदी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या दार्जिलिंग में फिर से हिंसा भड़काने की दुर्योजनाएं बन रही हैं?

बड़ी उम्मीद बंधी थी कि इस १९ नवंबर को गोरखालैण्ड मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष सुवास घीसिंग तथा केंद्र एवं पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच 'दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल' के प्रस्तावों पर समझौता हो जायेगा और पिछले २० महीनों से अशांत दार्जिलिंग की पहाड़ियों में अमन-चैन कायम हो सकेगा। सुवास घीसिंग ने यह भी घोषणा की थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन को वह 'शांति दिवस' घोषित करेंगे और सारे उग्रवादी गोरखा उस दिन अपने हथियार केंद्र सरकार को सौंप देंगे। उग्रवाद को ही गोरखालैण्ड स्थापना का एकमात्र मार्ग घोषित करनेवाले घीसिंग पिछले तीन महीनों से गोरखाओं को समझाते रहे थे कि गोरखालैण्ड समस्या का हल उग्रवाद से नहीं निकल सकता। पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल में जाकर गोरखा लोगों को कम-से-कम अपने लिए कुछ करने का मौका तो मिलेगा और गोरखालैण्ड प्राप्त करने का वही प्रथम सोपान होगा। उनका कहना था कि उग्रवादी तरीके अपनाने से गोरखाओं को भारतीय सेना का मुकाबला करना पड़ेगा और इस मुकाबले में गोरखा कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन सुवास घीसिंग ने निर्धारित १९ नवंबर के कुछ दिनों पहले ही अचानक पैंतरा बदल लिया। उन्होंने न

केवल पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, बल्कि पत्रकार इंद्रजीत खुल्लर सिक्किम के मुख्यमंत्री भंडारी और उनकी पत्नी जैसे लोगों को सरकार का एजेंट भी बताने लगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी बातचील कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।

समझौते की उम्मीद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को भी थी और वह १६ नवंबर को दिल्ली में ही थे, लेकिन सुवास घीसिंग ने अब एक सर्वथा नया मुद्दा उछाल दिया है। १९८२ और १९८५ में मार्क्सवादी सांसद आनंद पाठक द्वारा लोकसभा में 'दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष प्रावधान' के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। (जिसे दोनों बार लोकसभा ने नामंजूर कर दिया था।) इस विधेयक को मुद्दा बनाकर सुवास घीसिंग ने कहना शुरू कर दिया है कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र विकास कौंसिल में सिलिगुड़ी और डुअर्स के वे इलाके भी शामिल किये जायें जहां नेपाली रहते हैं। वास्तव में उक्त विधेयक में जो मांगे की गयी थीं, घीसिंग के अनुसार वे उनकी गोरखालैण्ड की मांगों से एक मायने में पूरी तरह मिलती-जुलती हैं। घीसिंग ने घोषणा कर दी है कि अब वह उक्त विधेयक की मांगों के आधार पर ही समझौता करेंगे। लेकिन पांच वर्ष पूर्व लोकसभा में श्री पाठक द्वारा प्रस्तुत विधेयक को घीसिंग ने आज अचानक मुद्दा क्यों बनाया? घीसिंग का कहना है कि पहले उन्हें इस विधेयक की जानकारी नहीं थी। २८ अक्तूबर को गृहमंत्री बूटा सिह से बात करके दार्जिलिंग लौटने पर इसकी जानकारी दार्जिलिंग जिला कांग्रेस-इ कमेटी के भूतपूर्व सचिव दौलत सिंह रासैली ने उन्हें दी थी। उक्त विधेयक के मसविदे से गोरखालैण्ड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गयी है। इस विधेयक का नेपाली भाषा में अनुवाद करके लाखों प्रतियां छापी जा रही हैं, जिन्हें व्यापक पैमाने पर बांटा जायेगा।

फिर टकराव का रास्ता: सुवास घीसिंग

विधेयक में क्या था?: सुवास घीसिंग उक्त विधेयक की दो धाराओं का खास तौर से हवाला देते हैं। धारा २४४ सी में कहा गया है, "संविधान में चाहे जो हो संसद कानून के द्वारा पश्चिम बंगाल प्रांत के अंतर्गत दार्जिलिंग और आसपास के जिलों के नेपाली बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी इलाका बना दिया जाये और प्रशासन के लिए एक जिला कौंसिल गठित की जाये। दूसरी धारा में उन विभागों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिन्हें इस स्वायत्तशासी जिला कौंसिल के अधीन करने की मांग की गयी थी, जिनमें शिक्षा, उद्योग, कृषि, खनिज, मनोरंजन, स्वास्थ्य जनकार्य पुलिस प्रवेश कर, भू राजस्व, सिंचाई, संचार, विद्युत कर आदि शामिल हैं।

घीसिंग की मांगें अंतहीन हैं: ज्योति बसु

घीसिंग इस विधेयक के समर्थन में श्री पाठक द्वारा दिये गये भाषण का भी हवाला देते हैं, जिसमें श्री पाठक ने कहा था कि यह विधेयक किसी भी तरह अलगाववादी या राजद्रोही आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। घीसिंग का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार उनके आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन अब हम भी तो उन्ही मांगों को उठा रहे हैं, जिन्हें मार्क्सवादी सांसद ने उठाया था और स्वयं ज्योति बसु ने विधानचंद्र राय के मुख्य मंत्रित्वकाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिनके लिए हंगामा बरपा किया था।

दूसरी ओर ज्योति बसु इस बात को सच नहीं मानते कि घीसिंग को उक्त विधेयक की पहले से जानकारी नही थी। उनका कहना है कि घीसिंग दार्जिलिंग में शांति के इच्छुक नहीं हैं और वह जब भी किसी समझौते के निकट पहुंचेंगे, तो कोई-न-कोई नयी मांग खडी कर देंगे—उनकी मांगें अंतहीन हैं। बहरहाल, गृहमंत्री बूटा सिंह ने १६ नवंबर को ज्योति बसु को आश्वस्त किया है कि सिलिगुड़ी और डुअर्स के नेपाली भाषी इलाकों को 'दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल' के प्रस्तावों में शामिल करने की मांग ही नहीं, किसी भी नयी मांग पर घीसिंग से बातचीत नहीं की जायेगी। ज्योति बसु प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बकौल ज्योति बसु प्रधानमंत्री ने संभवत: गोरखालैण्ड के बजाय अफ्रीका के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने को अधिक महत्वपूर्ण समझा।

बहरहाल, घीसिंग का संवाद अब केंद्र से टूट

प० बंगाल का विभाजन नहीं होगा: राजीव गांधी, ज्योति बसु और सुवास घीसिंग

चुका है, गोरखालैण्ड का मसला फिर वहीं जाकर खड़ा हो गया है, जहां से यह शुरू हुआ था। आखिर घीसिंग ने पहले जो मसला हिंसा से तय करना चाहा था, उसे बातचीत के जरिये तय करने का फैसला लेने के बाद अंतिम क्षणों में वह उससे पीछे क्यों हट गये?

समझौता प्रयास क्यों?: घीसिंग ने गोरखालैण्ड आंदोलन की शुरुआत हिंसक आंदोलनों से की थी। पश्चिम बंगाल सरकार बलपूर्वक इस आंदोलन को दबाने पर आमादा हो गयी, तो केंद्र सरकार ने गोरखालैण्ड आंदोलन के प्रति नरम रुख इसलिए अपनाया, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल की कांग्रेस-इ विरोधी वाममोर्चे की सरकार के लिए इसे सिरदर्द के रूप में खड़ा करना चाहती थी, लेकिन इसी नरम रुख ने घीसिंग को समझौता वार्ता द्वारा इस मामले को हल करने के लिए प्रेरित किया। २३ मार्च और १६ अप्रैल को घीसिंग ने केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि यदि गोरखाओं के लिए नागरिकता और सेना में अलग रेजिमेंट बनाने की व्यवस्था नहीं की जाती, तो हमें परिस्थितियों के दबाव में आकर सशस्त्र आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने उक्त दोनों मांगों को मानकर यह संकेत दे दिया कि वह बातचीत के जरिये गोरखाओं की समस्याओं को हल करने का इरादा रखती है। इसके बाद ही दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल का प्रस्ताव सामने आया। इससे सुवास घीसिंग का रुख कुछ नरम पड़ा और वह समझौता वार्ता करने के लिए राजी हो गये।

असल में यथार्थवादी सुवास बहुत पहले ही समझ गये थे कि इतनी कम ताकत लेकर चाहे जो हो सके, केंद्र और राज्य के संयुक्त पुलिस बल का बहुत दिनों तक सामना नहीं किया जा सकता। स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घीसिंग को बता दिया था कि किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल का विभाजन नहीं किया जायेगा। पश्चिम बंगाल का विभाजन करने का मतलब होगा, भारत की अखंडता को नष्ट करना। इसलिए जाति, भाषा या संप्रदाय के आधार पर राज्य गठित करने की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जायेगा। इसलिए गोरखालैण्ड आंदोलन का सपना देखना बंद कीजिए। दूसरी ओर घीसिंग यह भी समझ रहे थे कि दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। लंबे समय तक आंदोलन के कारण वह अर्थ-व्यवस्था चौपट होने लगी है। अतः घीसिंग ने अपने साथियों को समझाया कि पहले दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल के प्रस्ताव को मान लिया जाये, उसके बाद ताकत बढ़ाते हुए पृथक गोरखालैण्ड के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हुआ जाये।

> *घीसिंग ने अच्छी तरह समझ लिया था कि यदि उन्होंने केंद्र सरकार से पर्वतीय विकास कौंसिल के मामले पर समझौता कर लिया, तो वह उनके आंदोलनकारी साथियों के गले नहीं उतरेगा और यह भी संभव है कि घीसिंग को सरकार का आदमी मानकर ये आंदोलनकारी उन्हें ही आंदोलन से बाहर कर दें।*

पुलिस बल के भरोसे: दार्जिलिंग के पुलिस चीफ आर०के० डांडा

स्वागत व विरोध: घीसिंग के इस नरम रुख का शहरी क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि सशस्त्र आंदोलनों में वे ही सर्वाधिक नुकसान में रहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के गोरखालैण्ड समर्थक आंदोलनकारी घीसिंग के नेतृत्व के प्रति ही असंतोष व्यक्त करने लगे। उनका कहना है कि आंदोलन को संघर्ष के पथ पर न ले चलने से और प्रतीक्षा की नीति अपनाने से यह सारा आंदोलन ही व्यर्थ हो जायेगा। राज्य सरकार और पुलिस हावी होने लगेगी। निराशा के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। अंधकार की उस अनिश्चित स्थिति से बचने के लिए राज्य और केंद्र के विरुद्ध जुझारू आंदोलन को रोकने के बजाय और तीव्र कर देना चाहिए। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर पंजाब के ढंग पर आतंकवाद का सहारा भी लेना पड़े, तो पीछे नहीं हटना चाहिए।

गोरखालैण्ड मुक्ति मोर्चे से निष्कासित घीसिंग विरोधी नेता लाकपा शेरिंग दंग ने तो यहां तक आरोप लगाया कि सुवास घीसिंग तो राजीव गांधी और ज्योति बसु के इशारे पर गोरखा आंदोलन को खतम करने पर तुले हुए हैं। समझौता वार्ता और 'दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र विकास कौंसिल' को गोरखाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए दंग ने धमकी तक दे डाली कि पर्वतीय विकास कौंसिल में घीसिंग को भले ही कोई पद मिल जाये, लेकिन इससे दार्जिलिंग में अशांति दुगनी हो जायेगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लोग सिर्फ गोरखालैण्ड चाहते हैं. खिलौना देकर उनको बहलाने की कोशिश की गयी, तो तिस्ता और महानंदा का पानी खून से लाल हो जायेगा। समझौता विरोधी आंदोलनकारी ऐसे बयान देकर चुप नहीं हुए। मुक्ति मोर्चे के गढ़ गोरूबाथान, कार्शियंग और चायबागान के पहाड़ी क्षेत्रों में धड़ाधड़ पोस्टर लगने शुरू हो गये—

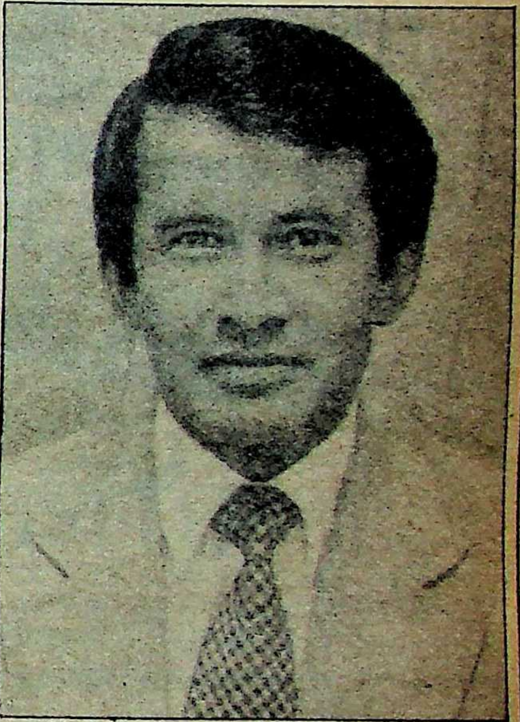
समझौते के सहयोगी या केंद्र के एजेंट?: नरबहादुर भंडारी

'गोरखालैण्ड के नाम पर विश्वासघात' नहीं चलेगा। ये आंदोलनकारी जुझारू आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में तहलका मचा देनेवाले घीसिंग को जुझारू रूप में ही देखना पसंद करते थे।

इस प्रकार घीसिंग मोर्चे के नरमपंथियों के बीच तो स्वीकार्य थे, लेकिन गरमपंथी उनसे नाराज हो गये। वैसे भी अपने नेतृत्व को कायम रखने के लिए घीसिंग के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह नरमपंथियों, खासकर शहरियों को विश्वास दिलायें कि वह खूनी राजनीति पसंद नहीं करते और संघर्षप्रिय ग्रामीणों के बीच वह अपनी जुझारू छवि को भी बनाये रखें। फलस्वरूप घीसिंग दोमुंही नीति अपनाने को मजबूर हो गये। कभी तो वह ज्योति बसु को सर्वाधिक ईमानदार मुख्यमंत्री बताकर उनकी प्रशंसा करने लगते, तो अचानक दूसरी सांस में वह उनके खिलाफ जहर उगलने लगते।

इधर सुवास घीसिंग समझौता वार्ता में आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर आंदोलनकारी इस मामले

सोवियत संघ
का उत्सव

नये जीवन
का निर्झर

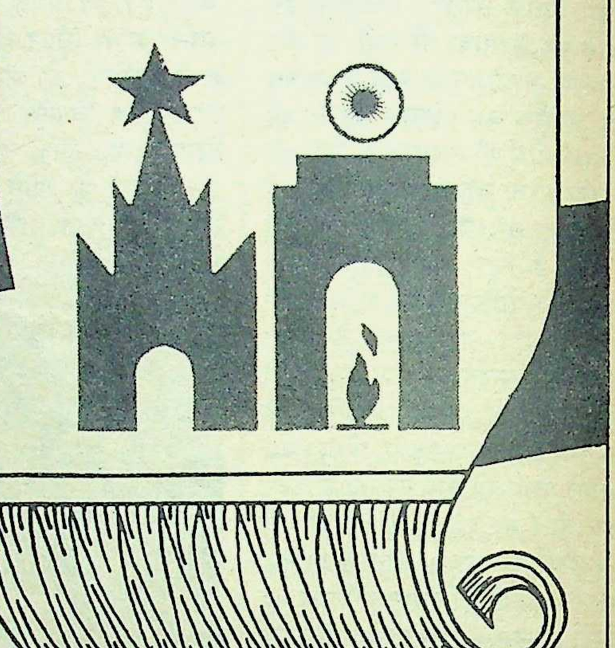

सोवियत संघ सचित्र मासिक पत्रिका

विश्व की बीस भाषाओं में प्रकाशित यह पत्रिका अपने पाठकों को सोवियत जीवन के सभी पहलुओं से, सोवियत जनता की रोजमर्रा की जिन्दगी और काम से परिचित कराती है ।

सोवियत पुरुषों और महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं तथा क्रियाकलापों में नये खुलेपन के वातावरण को प्रतिबिम्बित करती है ।

एक वर्ष २५ रुपये
तीन वर्ष ५० रुपये

उपहार :–

ग्राहक बनिए और
एक बहुरंगा कैलेण्डर
प्राप्त कीजिये
केवल तीन वर्ष के
ग्राहकों के लिए

साथ में २५/५० रुपये का डिमांड ड्राफ्ट/मनीआर्डर संलग्न है

नाम ______________________

पता ______________________

____

यह विज्ञापन और भुगतान निम्न पते पर भेजिये ----

मैगज़ीन सेन्टर,
एम. सी. डी. बिल्डिंग,
नं० २, दूसरी मंजिल
देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज
नई दिल्ली-११००५५

नवचेतन बुक्स (प्रा.) लि.
5 - ई, रानी झांसी रोड
नई दिल्ली - ११००५५

मनीषा ग्रन्थालय प्र. लि.
४/३, बी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-७०००७३

राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लि.
चमेलीवाला मार्केट, एम. आई. रोड
जयपुर – ३०२००२

SU-14

में परस्पर विरोधी खेमों में बंट रहे थे। जहां सुवास घीसिंग यह दावा करते थे कि उनके नेतृत्व को चुनौती देने की क्षमता पूरे दार्जिलिंग में नहीं है, वहीं वह यह भी अनुभव करने लगे थे कि आंदोलनकारियों में उनकी लोकप्रियता कम होने लगी है। गोरखालैण्ड आंदोलन में सुवास घीसिंग के बाद जुझारु नेता सी०के० प्रधान को दूसरे नंबर का नेता माना जाता था। समझौता प्रयासों का आलोचक बन जाने के कारण घीसिंग ने उन्हें मोर्चे से निकाल दिया था, जिसके कारण कालिम्पोंग के हजारों आंदोलनकारी घीसिंग के खेमे से मानसिक रूप से हट चुके थे। सी०के० प्रधान को हटाने का मतलब था, मोर्चे के एक स्तंभ को हिला देना, क्योंकि प्रधान अपने को घीसिंग का पुत्र मानते थे। सार्वजनिक रूप से वह ऐसा कहते भी थे। अपने साथियों की बातों में आकर घीसिंग प्रधान पर भरोसा नहीं रख सके। इसी प्रकार लाकपा शेरिंग देंग और उनके भाई को हटाकर भी घीसिंग ने ऐसी ही भूल की। इससे कालिम्पोंग का विस्तृत ग्राम्यांचल और कार्शियंग का कुछ हिस्सा भी घीसिंग के हाथ से निकल गया। यदि शुरू से घीसिंग गोरखा आंदोलन के लिए लोकतांत्रिक व नरम रुख अपनाते, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। घीसिंग भी यह अनुभव करने लगे थे कि मोर्चे में फूट पड़ गयी है। मोर्चे में ऐसा सोचनेवालों की संख्या बढ़ने लगी थी कि केंद्र सरकार के निमंत्रण और पर्वतीय कौंसिल गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करके घीसिंग ने कट्टरपंथियों और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। कट्टरपंथी एक प्रकार से इसे अपनी हार मानने लगे थे। एक आंदोलनकारी का कहना था, "इस क्षेत्र की, जनता गोरखा मुक्ति मोर्चे को नहीं, अलग गोरखालैण्ड की मांग को जानती है। इसलिए बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने की तरह इस समझौते को अस्वीकार कर जनता फिर जुझारू आंदोलन शुरू कर देगी। उसको रोकने की ताकत खुद घीसिंग में नहीं है। तब उन्हें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शरणार्थी शिविर या पुलिस कप्तान के रिटायरिंग रूम में शरण लेने के लिए भागना पड़ेगा और फिर घीसिंग उस समय गोरखालैण्ड आंदोलन के खूनी संघर्ष के पराजित साक्षी बनकर रह जायेंगे।"

फिर पैंतरा बदला : घीसिंग ने अच्छी तरह समझ लिया था कि यदि उन्होंने केंद्र सरकार से पर्वतीय विकास कौंसिल के मामले पर समझौता कर लिया, तो वह उनके आंदोलनकारी साथियों के गले नहीं उतरेगा और यह भी संभव है कि घीसिंग को सरकार का आदमी मानकर ये आंदोलनकारी उन्हें ही आंदोलन से बाहर कर दें। तब हालत यह होगी कि गोरखालैण्ड आंदोलन और भी उग्र रूप धारण कर लेगा, लेकिन उसका नेतृत्व करने के लिए घीसिंग वहां नहीं होंगे। यही वजह है कि अक्तूबर बीतते-बीतते उन्होंने समझौते से हट जाने का मन बना लिया था और २८ अक्तूबर को दिल्ली में गृहमंत्री बूटा सिंह से बात करके दार्जिलिंग लौटने के बाद उन्होंने नयी-नयी मांगें रखनी शुरू कर दीं और ऐन मौके पर जब 'दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र विकास कौंसिल' के मसविदे को अंतिम रूप दिया जाना था, उन्होंने मार्क्सवादी सांसद आनंद पाठक द्वारा पांच वर्ष पूर्व लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक का मामला उठाकर समझौते से किनाराकशी कर ली।

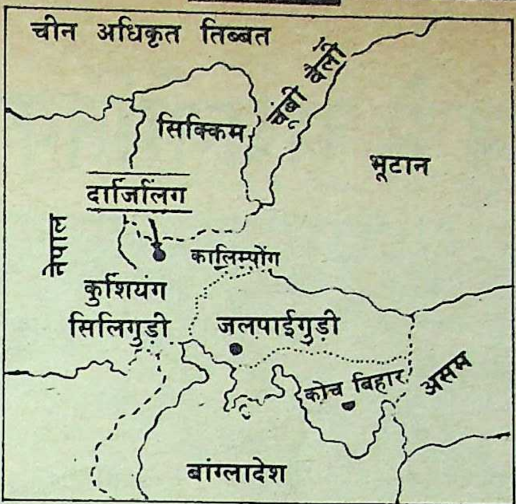

गोरखालैण्ड के प्रस्तावित इलाके

> *गृहमंत्री बूटा सिंह ने १६ नवंबर को ज्योति बसु को आश्वस्त किया है कि सिलिगुड़ी और डुअर्स के नेपाली भाषी इलाकों को 'दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र विकास कौंसिल' के प्रस्तावों में शामिल करने की मांग ही नहीं, किसी भी नयी मांग पर घीसिंग से बातचीत नहीं की जायेगी।*

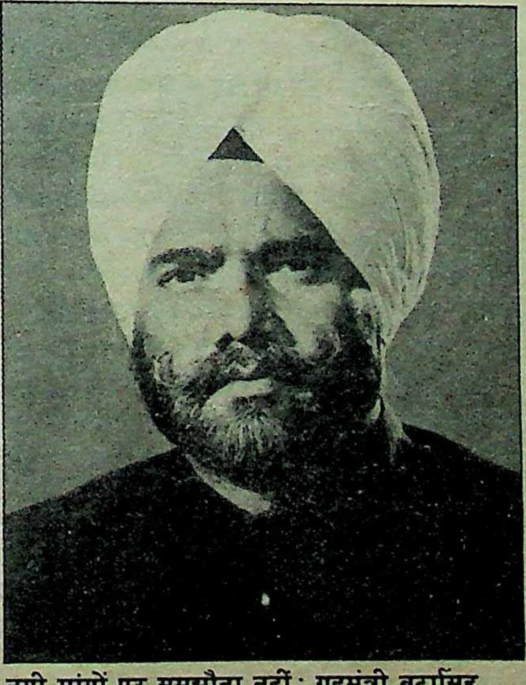

नयी मांगों पर समझौता नहीं : गृहमंत्री बूटासिंह

क्या दार्जिलिंग फिर सुलगेगा : घीसिंग द्वारा समझौता प्रयासों से हट जाने के कारण दार्जिलिंग में व्याप्त अनिश्चय की स्थिति दूर हो गयी है। दो खेमों में बंट चुके आंदोलनकारियों को घीसिंग की यह किनाराकशी क्या आंदोलन तेज करने का संकेत तो नहीं है? क्या दार्जिलिंग की शांत, शीतल मनोरम घाटियां फिर अशांत हो जायेंगी? इस सवाल ने पश्चिम बंगाल सरकार को परेशान कर दिया है। वैसे भी आज दार्जिलिंग में जो शांति दिखाई दे रही है, उसका कारण है, अर्धसैनिक बलों का आतंक। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बी०एस०एफ० और सी०आर०पी० के जवान यहां से हट जायें, तो पूरा प्रशासन चरमराकर ढह जायेगा। दार्जिलिंग में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी यह महसूस करते हैं कि दार्जिलिंग का बच्चा-बच्चा गोरखालैण्ड समर्थक है। मजाक में यहां तक कहा जाता है कि पुलिस के अधिकारी तक जरूरी संदेश टेलीफोन से भेजने का साहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय है कि गोरखालैण्ड समर्थक टेलीफोन एक्सचेंज में हैं और उनका संदेश आंदोलनकारियों तक पहुंच जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस चीफ आर०के० हांडा तक में हिम्मत नहीं है कि वे सशस्त्र रक्षकों के बिना शहर में निकल आयें। पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों का जो दबदबा है, वह शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि देहाती क्षेत्रों में तो जैसे गोरखालैण्ड स्थापित ही हो चुका है। खुखरीधारी गोरखा आंदोलनकारी देहाती क्षेत्रों में सक्रिय हैं और उन इलाकों के चायबागानों की जमीनों पर गोरखा कब्ज़ा करते जा रहे हैं। दूसरी ओर चायबागान के मालिकों पर दोतरफा मार पड़ रही है। आंदोलनकारी वहां खड़े हरे पेड़ काट जाते हैं और चायबागान के अधिकारी जब इसकी शिकायत करते हैं, तो पेड़ काटने के जुर्म में उन्हीं पर जुर्माना हो जाता है, लेकिन गोरखा आंदोलनकारियों को पकड़ने की हिम्मत पुलिस नहीं दिखाती। खुखरीधारी गोरखा आंदोलनकारियों का इतना आतंक है कि गत १० नवंबर को बी०एस०एफ० फायरिंग के विरुद्ध गोरखा आंदोलनकारियों ने दार्जिलिंग में चक्का जाम किया, तो एक भी वाहन न तो शहर में घुस सका और न ही शहर से बाहर जा सका और हजारों राइफलधारी जवान मूक दर्शक की तरह दिनभर चक्का जाम का दृश्य देखते रहे।

स्पष्ट है, दार्जिलिंग ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है और गोरखालैण्ड आंदोलन के नेता सुवास घीसिंग ने बातचीत के जरिये समझौता करने का रास्ता छोड़ दिया है। क्या घीसिंग दार्जिलिंग की हरी-भरी वादियों को एक बार फिर आंदोलन की आग में झोंक देंगे?

—अमित विक्रम राणा, कलकत्ता ब्यूरो

श्रीलंका में शांति सेना

तमिलनाडु में राजनीतिक उबाल

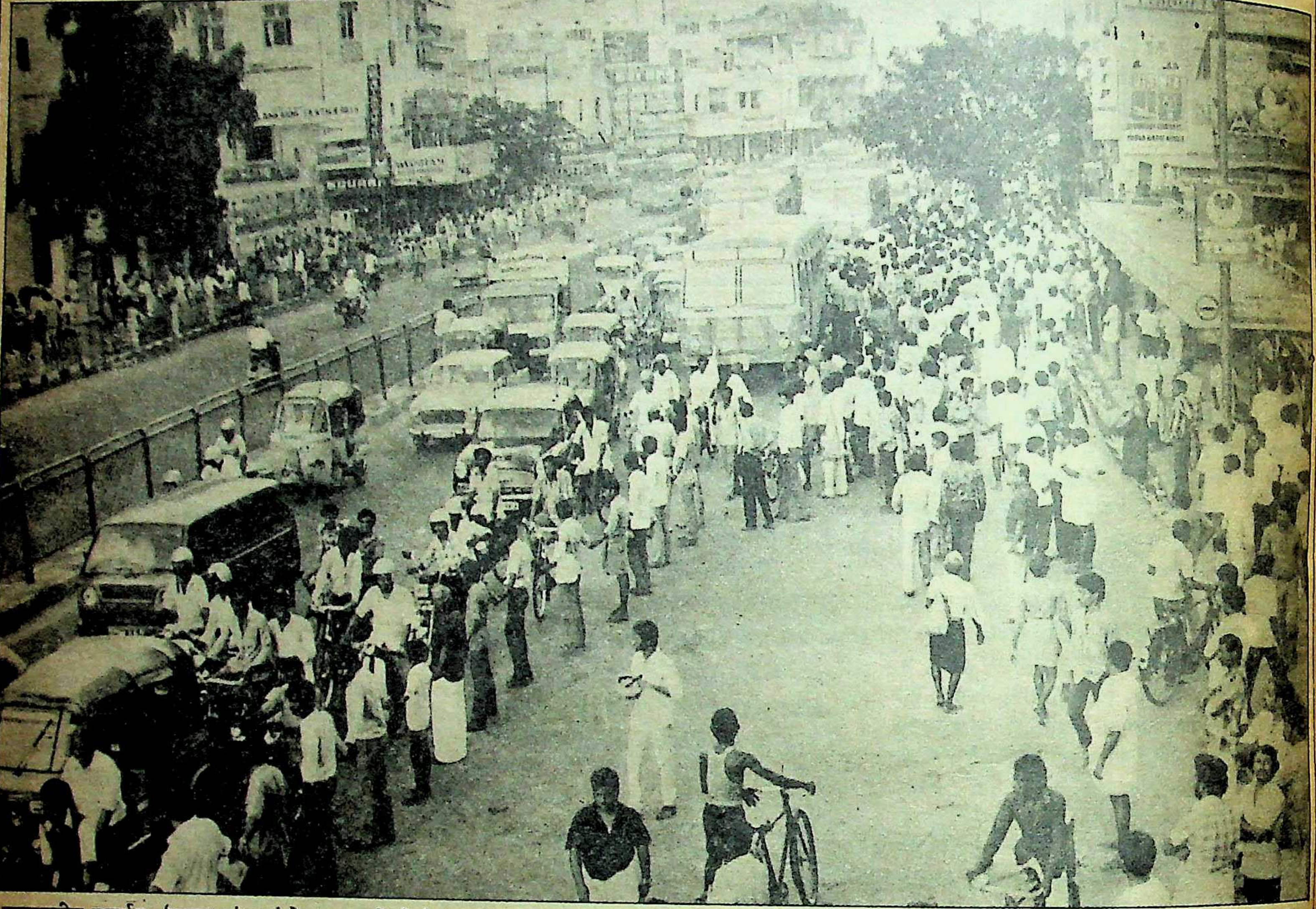

उत्साहहीन समर्थन: 'मानव शृंखला' के माध्यम से विरोध-प्रदर्शन

अभी तक तमिलनाडु में हिन्दी को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह श्रीलंका में शांति सेना की कार्यवाही के मुद्दे ने ले ली है। क्योंकि मुख्यमंत्री एम०जी०आर० केन्द्र की नीति का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए करुणानिधि मौके का फायदा उठाने के लिए शांति सेना की कार्यवाही का घोर विरोध कर रहे हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम०जी० रामचंद्रन द्वारा श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के हर कदम का समर्थन करने की खुली घोषणा के बाद अन्नाद्रमुक (अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम) और कांग्रेस-इ के बीच संभावित दो फाड़ की संभावना फिलहाल टल गयी है। लेकिन इस बात को याद रखना होगा कि चाहे एम०जी०आर० बीमार भले ही हों, वह चतुर इतने हैं कि शायद ही कभी गलत पत्ते फेंके हों। एम०जी०आर० के अमरीका चले जाने के बाद विपक्षी पार्टी द्रमुक (द्रविड़ मुनेत्र कषगम) ने उनकी अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाया। लिट्टे (लिबरेशन आफ तमिल टाइगर्स ईलम) का समर्थन करके उसने खासी लोकप्रियता अर्जित कर ली। वैसे देखा जाये, तो करुणानिधि और लिट्टे के सर्वेसर्वा प्रभाकरण के कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। प्रभाकरण हमेशा एम०जी०आर० के भक्त रहे और एम०जी०आर० ने भी उन्हें खूब संरक्षण दिया, लेकिन रातोरात राजनीतिक समीकरण बदल गये और दोस्त से कट्टर दुश्मन बन गये।

द्रमुक को जीवन दान: श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप से मृतप्राय द्रमुक को जैसे जीवनदान मिल गया। उसने लिट्टे का जमकर समर्थन किया और यह मुद्दा उसके लिए समस्या गहराने के साथ-साथ लाभप्रद बनता गया। अभी तक द्रमुक के पास हिंदी विरोध का मुद्दा पुराना पड़ रहा था। लेकिन श्रीलंका की बदलती परिस्थितियों से उसे विरोध का एक और मुद्दा मिल गया। उसने भारतीय शांति सेना पर आरोप लगाया, "श्रीलंका में तमिलों को मारकर वह बहुत बड़ा अपराध कर रही है। लिट्टे सोच रहा था कि शांति सेना जाफना के लोगों को आजाद कराने आ रही है, मगर वह तो दमन कर रही है।" माहौल बनाने के लिए द्रमुक तरह-तरह के नाटकीय तरीके इस्तेमाल कर रही है। करुणानिधि को पता है कि लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काया जा सकता है और अपने इस 'ज्ञान' का वह भरपूर फायदा उठा रहे

हैं। 'मानव श्रृंखला' से काफी संख्या में लोग द्रमुक की तरफ झुके हैं। यह प्रदर्शित करने के लिए दूरदर्शन शांति सेना की कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण ढंग से दिखला रहा है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक टेलीविजन को हथौड़ा मारकर तोड़ा। ६ नवंबर को सैकड़ों नेत्रहीनों और अपाहिजों ने अन्ना सलाई (मद्रास) में हाथ-से-हाथ बांधकर शांति सेना की कार्यवाही का विरोध करते हुए लड़ाई खतम करने की मांग की। तमिल ईलम के अधिकारों की रक्षा के नाम पर आयोजित 'मानव श्रृंखला' में ऐसे भी लोग थे जो मात्र तमाशबीन की हैसियत से शामिल थे। वैसे इसमें कई द्रमुक सांसदों ने भी हिस्सा लिया, मगर जैसा कि साफ है कांग्रेस-इ और अन्नाद्रमुक इससे दूर रहे। 'मानव श्रृंखला' के लोग राजीव गांधी और शांति सेना के विरोध में तथा लिट्टे और प्रभाकरण के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

११ नवंबर को कोयंबतूर में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने १० किलोमीटर की 'मानव श्रृंखला' बनायी। द्रमुक द्वारा आयोजित 'मानव श्रृंखला' में सैकड़ों समाजसेवी, वकील, व्यापारी और शिक्षक शामिल हुए। कोयंबतूर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने काले कार्ड लगाकर शांति सेना की कार्यवाही का विरोध किया। ठीक उसी दिन करुणानिधि ने पार्टी कार्यकर्ताओं से श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा, "प्रायद्वीप के तमिलों की राय लिये बिना राजीव गांधी को समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। समझौता श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच होना चाहिए।" कार्यकर्ता तुरंत उनकी इस मुहिम में शामिल हो गये। द्रमुक सांसद एन०वी०एन० सोमू ने लोकसभा में बड़े ही भावुक स्वर में कहा, "तमिलों के छोटे से दल को निहत्था करने के लिए शांति सेना बमबारी क्यों कर रही है?" उन्होंने आगे कहा, "भारतीय सेना महान है, उसका पिछला रिकार्ड शानदार रहा, मगर शर्म की बात है कि एक आदमी के 'अहं' को तुष्ट करने के लिए आज वह भाड़े का टट्टू बन गयी है। भारत को तमिलों का उद्धारक बनना चाहिए और बंगलादेश की तरह स्वतंत्र मातृभूमि के उनके सपने को पूरा करने में मदद करनी चाहिए।"

पार्टी में विभाजन: एम०जी०आर० अमरीका से लौटने के बाद मैदान में आये। लौटने पर उन्होंने पाया कि पार्टी श्रीलंका के मुद्दे पर दो धड़ों में विभाजित हो गयी है। एक धड़ा श्रीलंका में भारत सरकार की कार्यवाही को समर्थन देना चाह रहा था, तो दूसरा धड़ा कार्यवाही का विरोध करने की धमकी दे रहा था। शांति सेना और लिट्टे के बीच युद्ध शुरू होने के बाद एम०जी०आर० ने बाल्टीमोर से राजीव गांधी को तार भेजा। राजीव गांधी उस समय राष्ट्रमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए वैंकुवर (कनाडा) में थे। तार में एम०जी०आर० ने जाफना में पुनः शांति बहाल करने पर जोर दिया था। अमरीका से लौटने पर एम०जी०आर० ने एक और तार भेजा। इस तार में उन्होंने लिट्टे के विश्वस्त सहयोगी और जाफना के पूर्व नगरपालिका आयुक्त वी० शिवज्ञानम की उस अपील को मान लेने की सलाह दी थी, जिसमें ४८ घंटे के युद्ध विराम की बात कही गयी थी, ताकि लिट्टे अपने हथियार सौंप सके। जवाब में विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह ने व्यक्तिगत बातचीत के लिए उन्हें दिल्ली बुला भेजा। एम०जी०आर० ने मद्रास में लिट्टे नेता सदाशिवम कृष्ण कुमार उर्फ किट्टू से भी दो बार मुलाकात की, लेकिन तमिलनाडु के वित्तमंत्री वी०आर० नेदुचेझियन ने विधानसभा में कहा कि इस समय इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कितनी बातचीत की जानी चाहिए, इसका फैसला केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं।

एम०जी०आर० का यह बयान कि "श्रीलंका के मामले पर तमिलनाडु केंद्र के साथ है" अभी तक एकमात्र ऐसी खुली घोषणा है जो उनकी सरकार का रवैया स्पष्ट करती है। लेकिन यह दिलचस्प है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी के नेता अलादी अरुणा ने उनके बयान को अनदेखा कर दिया। अलादी अरुणा ने केंद्र की आलोचना करते हुए व्यंग्य किया, "यदि केंद्र को यह मालूम न हो कि लिट्टे को कैसे राजी (युद्ध विराम के लिए) किया जाये, तो इसे हमारे मुख्यमंत्री एम०जी०आर० पर छोड़ दे।" यहां तक कि तमिलनाडु में एक भी अन्नाद्रमुक सदस्य यह नहीं मानता कि केंद्र श्रीलंका मुद्दे पर ठीक-ठाक सोच रहा है या ठीक कार्यवाही कर रहा है और इससे राज्य में उसे कुछ लोकप्रियता मिल सकेगी। अरुणा के बयान पर राजीव गांधी ने संसद में कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और एम०जी०आर० के साथ इस मुद्दे पर उनके कोई मतभेद नहीं हैं।

संकटपूर्ण स्थिति: एम०जी०आर० इस समय विकट परिस्थितियों में फंसे हैं। इस समय हर कदम उन्हें फूंक-फूंककर रखना पड़ेगा। राज्य से लंबी गैरहाजिरी के कारण नयी परिस्थितियों ने जन्म लिया है। लिट्टे नेता प्रभाकरण ने उनका साथ छोड़कर करुणानिधि का दामन थाम लिया है। उनकी गैर मौजूदगी में उनका कार्यभार संभालने वाले खाद्यमंत्री एस० रामचंद्रन, जो कांग्रेस-इ समर्थक माने जाते हैं, ने राजीव गांधी की लाइन पर काम किया और एम०जी०आर० की नीतियां गडबडा गयीं। अब एम०जी०आर० को इस बात पर ध्यान देना होगा कि उभरते विपक्ष को कैसे दबाया जाये। उनकी पार्टी के अपने तीन सदस्य विपक्षी द्रमुक के अभियान का समर्थन कर रहे हैं। ये हैं: कालीमुथु, वालंपरी जान और अलादी अरुण। इनके तेज-तर्रार भाषण स्थिति को और विस्फोटक बना रहे हैं। अतः यदि एम०जी०आर० को अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उन्हें तमिलों की भावनाओं के साथ अपनी हमदर्दी जतानी होगी।

यह काबिले गौर है कि अमरीका से लौटने के बाद एम०जी०आर० ने सबसे पहले एस० रामचंद्रन से १० विभाग वापस ले लिये और श्रीलंका के मामले में उनकी दखल भी बंद कर दी। इसी तरह एक साल पहले सूचना मत्री के पद से हटाये गये आर०एम० वीरप्पन को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। वीरप्पन द्रमुक के समर्थक जय ललिता के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। बहरहाल, वीरप्पन वापसी के बाद अब अन्नाद्रमुक में बिखराव की संभावनाएं कम हो गयी हैं। एम०जी०आर० ने भी अब चुप्पी साध ली है। हाल में जब पार्टी के सहायक महासचिव के० कालीमुथु ने रक्षामंत्री के०सी० पंत की इसलिए आलोचना की कि उन्होंने राष्ट्रपति जयवर्धन को प्रभाकरण को पकड़ने की कीमत एक करोड़ रुपए तय करने की इजाजत क्यों दी, तो

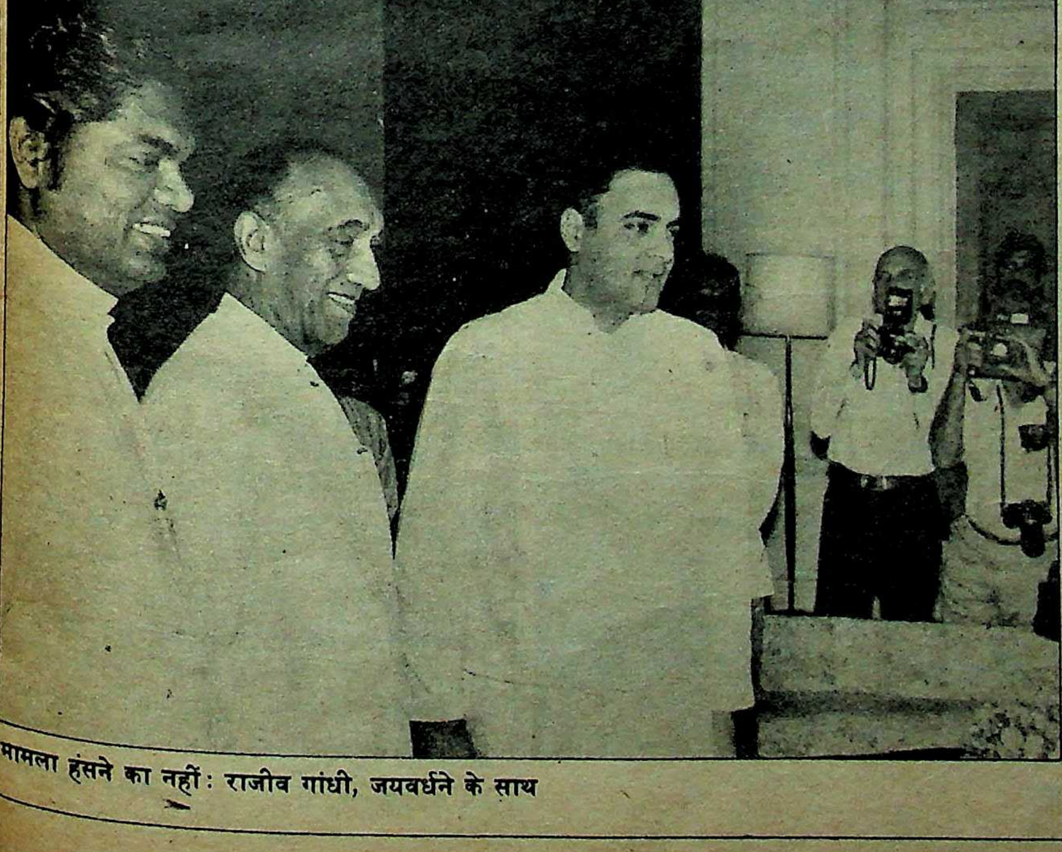

मामला हंसने का नहीं: राजीव गांधी, जयवर्धने के साथ

एम०जी०आर० चुप रहे। बताया जाता है कि कालीमुथु ने यह भी कहा कि यदि वह पंत और जयवर्धने की बैठक के दौरान उपस्थित होते, तो वह जयवर्धने का सिर काट कर उससे फुटबाल खेलते।

एम०जी०आर० ने विदेश से लौटने के बाद एक और महत्वपूर्ण काम किया। शांति सेना की कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किये गये २०,००० द्रमुक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री एम०जी०आर० पर छोड दे।" यहां तक के इस आदेश के पहले तक उन्हें १५ दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश थे। इन सब कार्यवाहियों के बाद ऐसा समझा जाने लगा था कि अब वह कांग्रेस- इ से नाता तोड़ने वाले हैं, लेकिन ताजा बयान में भारत सरकार की कार्यवाहियों का समर्थन करके उन्होंने सारी अफवाहों को गलत साबित कर दिया है। एक तथ्य यह भी है कि जयवर्धने के हाल के बयान से उन्हें गहरी चोट पहुंची होगी। जयवर्धने ने तमिलनाडु सरकार की यह कहकर आलोचना की है कि वह लिट्टे छापामारों को हथियार और शरण दे रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि तमिलनाडु सरकार उन्हें मदद न दे रही होती, तो हमने कब के हथियार रखवा लिए होते। बाद में जयवर्धने ने अपने बयान को लचीला बनाने की कोशिश की, मगर तीर तब तक चल चुका था।

राजनीतिक पुनर्जीवन: करुणानिधि प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए

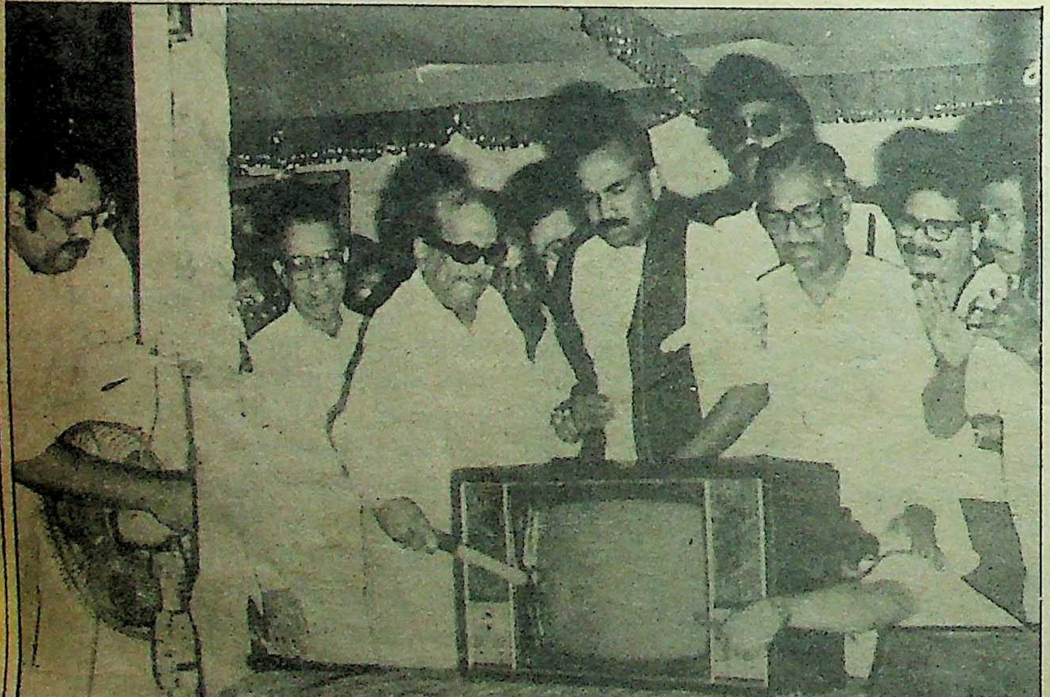

'कुप्रचार' का विरोध: करुणानिधि टी०वी० सेट तोड़ते हुए

जहां तक तमिलनाडु की जनता का सवाल है, वह ज्यादा क्षोभ महसूस नहीं कर रही है। वह इसे दूसरे का मामला समझती है। अगर शांति सेना की कार्यवाही पर बात करती भी है, तो चाहती है कि मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना चाहिए। "हम किसी दूसरे की धरती पर दूसरे के लिए क्यों लड़ रहे हैं?" यह सवाल आम तौर पर पूछा जा रहा है। वे लोग भी जो लिट्टे को गलत मानते हैं, चाहते हैं कि लड़ाई बंद करके शांति बहाल करवानी चाहिए। मद्रास का एक व्यक्ति कहता है, "हम भयंकर सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं, शहर में पानी की बेहद कमी है, हमारी रोजमर्रा की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यह आशा कैसे की जा सकती है कि श्रीलंका और श्रीलंकाई तमिलों की हालत से हम चिंतित हों। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ़ना चाहिए और भारत से सुलझाने की आशा नहीं रखनी चाहिए।" हाल में हिंदू और आई०एम०आर०बी० (इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो) ने एक जनमत संग्रह कराया था। जनमत संग्रह से पता चला कि तमिलनाडु के शहरी क्षेत्र के ज्यादातर लोग शांति सेना की कार्यवाही का समर्थन करते हैं। जनमत संग्रह से निम्नलिखित बातें सामने आयी:

शांति सेना की कार्यवाही का जबर्दस्त समर्थन और लिट्टे से आत्मसमर्पण कर देने की मांग।

आम तौर पर यह विचार पाया गया कि लिट्टे का वर्तमान रवैया गलत है।

यह पूछने पर कि लिट्टे छापामार 'स्वतंत्रता सेनानी' हैं या 'दिग्भ्रमित युवक,' ज्यादातर लोग दुविधाग्रस्त दिखे।

ज्यादातर लोग जयवर्धने की नीयत पर शक कर रहे हैं।

भारत-श्रीलंका समझौते का जबर्दस्त समर्थन। यह अप्रत्याशित नहीं कि जुलाई में समर्थन का जो जोर था, अब उतना नहीं।

शांति सेना पर करुणानिधि द्वारा लगाये गये आरोपों से जोरदार असहमति।

तमिलनाडु के तमिलों के लिए लिट्टे के छापामार अड़ियल हैं और उनसे उनका कोई खास ताल्लुक नहीं है। वे सोचते हैं कि यह एक राजनीति का खेल है। जयवर्धने ने अपने देश का रक्षा-व्यय भारतीय सेना पर थोपकर कम कर लिया है। वह अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों से वायदा कर रहे हैं कि भारतीय सेना जब तक चाहे रह सकती है। मैकियावेली ने एक बार ठीक कहा था कि वह मूर्ख है जो अपना युद्ध खुद लड़ते हैं और जयवर्धने निश्चित रूप से मूर्ख नहीं हैं। **—विशेष संवाददाता**

नयी फसल के बावजूद सब्जियां महंगी

अभी तो महंगाई और बढ़ेगी

सूखे और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए देश के अर्थशास्त्री इन सर्दियों में घोर महंगाई की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन अभी से जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। विशेषज्ञ जितना अंदाजा लगा रहे थे,वस्तुएं उससे भी अधिक महंगी क्यों हो रही हैं? इस महंगाई की मार सबसे ज्यादा किस वर्ग पर पड़ेगी?"

आनेवाली सर्दियां भारत के अधिकांश लोगों के लिए कष्टकर साबित होंगी। इसलिए नहीं कि इस साल कुछ अधिक सर्दी पड़ेगी, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति जो खाता, पहनता और रोजमर्रा जरूरतों की जो वस्तुएं इस्तेमाल करता है, उनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यह महंगाई असाधारण होगी। सूखे और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए घोर महंगाई का जो अंदाजा लगाया गया था, वस्तुएं उससे भी अधिक महंगी हो जायेंगी। मध्य नवंबर में ही यह हाल है कि नयी फसल बाजार में आ जाने के बावजूद आलू पिछले महीने से अधिक महंगा है। पिछले कई महीनों से प्याज पांच से छह रुपए प्रतिकिलो बिक रही थी, लेकिन इधर दिल्ली के कई बाजारों में उसके भाव सात रुपए प्रतिकिलो हो गये हैं। यहां तक कि पालक, मैथी, बथुआ जैसे साय या बैगन तक४ रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। टमाटर तो खैर १२ रुपए प्रतिकिलो है ही। खीरा भी १२ रुपए प्रतिकिलो से अधिक है। केवल बंदगोभी व फूलगोभी ही कुछ सस्ते हुए हैं, फिर भी इतने महंगे हैं, जितने कि इस मौसम में नहीं होने चाहिए। खाद्य तेलों और खाद्यान्न की कीमतों में इस मौसम में हमेशा कमी आ जाती थी, लेकिन इस वर्ष यह नदारद है। खाद्य तेलों के भाव एक बार एक-दो सप्ताहों के लिए जरूर गिरे, लेकिन फिर चढ़ने शुरू हो गये।

खाद्य तेलों को आयात करने का भारत सरकार का फैसला भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि थोक विक्रेता और अधिक मूल्य वृद्धि की आशा में खाद्य तेलों का अपना स्टाक दबाकर बैठ गये हैं। वे जानते हैं कि खाद्य तेलों के आयात मात्र से खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि नहीं रुकेगी। पता चला है कि अकाल के कारण गुजरात में तेल बीज की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। जब फसल कटाई का मौसम निकल जायेगा और खाद्य तेलों की वास्तविक कमी आने के कारण इसके भाव अनापशनाप बढ़ जायेंगे, तब जाकर खाद्य तेलों के जमाखोर अपना भंडार बाजार में लायेंगे और फुटकर विक्रेता भी अभाव की स्थिति का लाभ उठाकर इसके भाव और भी अधिक बढ़ा देंगे।

खाद्यान्न के मामले में भी हूबहू यही स्थिति है। भारत सरकार बार-बार यह घोषणा करती रही है कि उसके पास अभाव की स्थिति में लोगों का पेट भरने के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार है। इसके

गरीब के लिए दुर्लभ वस्तुएं

बावजूद गेहूं, दाल, चावल, ज्वार, बाजरा के भावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

मुद्रास्फीति : विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष मुद्रास्फीति गत वर्ष के मुकाबले दुगनी हो जायेगी। इसका मतलब है कि यह १० से २० प्रतिशत के बीच बढ़ेगी। वाणिज्य शोध ब्यूरो ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि भी मंहगाई के संबंध में खतरनाक संकेत देती है, क्योंकि यह सारी आबादी को अर्थात हर आय वर्ग को समान रूप से प्रभावित करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में हो रही वृद्धि भी मंहगाई के बढ़ने का पूर्वाभास दे रही है। मार्च, १९८७ से २४ अक्तूबर के बीच थोक मूल्य सूचकांक में ८.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि गत वर्ष इसी दौरान यह वृद्धि सात प्रतिशत थी। यह तो सरकारी आंकड़ा है, वास्तविकता में यह अंतर और भी बड़ा है। इधर खाद्यान्नों और रोजमर्रा जरूरत की वस्तुओं के दाम गत वर्ष के मुकाबले कहीं अधिक तेज गति से बढ़े। गतवर्ष इसी अवधि में इनकी कीमतों में ५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी जब कि इस वर्ष इस दौरान यह वृद्धि ८ प्रतिशत रही।

भावों में वृद्धि : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हो रही वृद्धि तो सारा नजारा ही स्पष्ट कर देती है। सितंबर, १९८७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में यह वृद्धि दस प्रतिशत थी, जबकि गत सितंबर के पूर्व छह मासों में खाद्य तेलों की कीमतों में ३०.६ प्रतिशत, खाद्यान्न की कीमतों में ७.३ प्रतिशत और दूध तथा दूध से बने पदार्थों की कीमतों में १२.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दौरान खाद्य तेलों के मूल्य प्रति रुपए ३० पैसे, खाद्यान्न के ७ पैसे और दूध तथा दूध से बने पदार्थों में प्रति रुपए १२ पैसे बढ़े और मूल्य-वृद्धि का यह क्रम जारी है। इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की कुल वृद्धि में से करीब आधे के लिए (वास्तविक संख्या ४६ प्रतिशत) खाद्यान्न एवं रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जिम्मेदार रही है। आनेवाले दिन कैसे होंगे? यह मुख्यतः खाद्यान्न की स्थिति पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों की राय है कि इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन के दस प्रतिशत कम होने के सारे आसार मौजूद हैं। इसका मतलब है कि गत वर्ष देश में जितना खाद्यान्न था, इस वर्ष उसमें दस प्रतिशत की कमी हो जायेगी, लेकिन दूसरी ओर देश की जनसंख्या इस वर्ष दो प्रतिशत बढ़ जायेगी। दस प्रतिशत खाद्यान्न की कमी और खानेवालों में दो प्रतिशत वृद्धि का अर्थ यह हुआ कि गत वर्ष जहां प्रतिव्यक्ति औसतन एक किलो खाद्यान्न उपलब्ध था, इस वर्ष यह उपलब्धता घटकर ८८० ग्राम रह जायेगी।

गरीब पर कहर : खाद्य तेल, खाद्यान्न, फल व सब्जियां आदि ऐसी वस्तुएं हैं, जिन पर व्यक्ति की आमदनी का सर्वाधिक हिस्सा व्यय होता है। जिनकी आमदनी ३ हजार से चार हजार रुपए प्रति मास के बीच है (जो मकान का किराया भी देते हैं) उनकी आमदनी का पचास प्रतिशत अकेले भोजन पर व्यय होता है। इस प्रकार जिनकी आमदनी इससे जितनी कम होती जायेगी, वैसे-वैसे भोजन पर व्यय होने वाला उनकी आमदनी का प्रतिशत भी बढ़ता जायेगा। लोगों को गैरजरूरी वस्तुओं पर होने वाले खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि का रुख गरीब पर ही सबसे ज्यादा कहर ढाता है। सर्दियों के मौसम में वह रोटी के साथ अकसर प्याज और आलू एवं साग की सस्ती किस्मों से अपना काम चलाता है। खाद्य तेल का इस्तेमाल वह सब्जी दाल को छौंकने में करता है। यह वह वर्ग है जो किलो या ग्राम के हिसाब से खाद्यतेल नहीं खरीद पाता। कभी ५० पैसे का तेल लेगा या एक रुपए का। आनेवाले दिनों में उसे बिना खाद्य तेल के ही काम चलाना पड़ेगा और जब उसे दाल और सब्जी भी मयस्सर नहीं होगी, तो वह प्याज और मिर्च से ही अपना काम चलायेगा। दालों का प्रयोग तो उसके बस के बाहर होता ही जा रहा है। सौ ग्राम मसूर, चना या उड़द के लिए उसे फिलहाल ७५ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अगले सप्ताह यह खर्च बढ़कर ८० पैसे उससे अगले सप्ताह ८५ पैसे और इसी क्रम से उसका खर्च बढ़ता चला जायेगा। वे गरीब जिन्हें सप्ताह में केवल तीन से सात वक्त का भोजन नसीब है, उन्हें तो सीधे-सीधे भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

छाया : रंजन बसु

—मालिनी चक्रवर्ती

योजना आयोग

एक मरणासन्न संस्था

देश के सुनियोजित विकास के लिए योजना आयोग की अहम भूमिका है। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय इस संस्था का जो महत्व था, क्या वही महत्व अब भी है? क्या अब योजना आयोग मात्र एक मरणासन्न संस्था बन कर रह गया है? क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी योजना आयोग की निरंतर उपेक्षा कर रहे हैं?

योजना आयोग के प्रति सरकार का रुख देखकर योजना भवन में बैठे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने देश के सुनियोजित आर्थिक विकास की जो परिकल्पना की थी, वह अधूरी ही रहेगी। वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के उपाध्यक्ष के पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि उनकी जगह, उन्हीं के समान कोई सुयोग्य व्यक्ति बिठाया जाता। प्रधानमंत्री को इस जगह के लिए जो व्यक्ति सूझा, वह विधिमंत्री शिवशंकर हैं जो न जाने किन कारणों से योजनामंत्री के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं।

बहरहाल, शिवशंकर को योजना आयोग के उपाध्यक्ष-पद पर बिठाने का कारण जो भी रहा हो, लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में योजना आयोग और प्रधानमंत्री सचिवालय के बीच निश्चित रूप से दूरी बढ़ी है। वित्त सचिव, विश्व बैंक से संबद्ध अर्थशास्त्री और अब 'सेंटर फार पालिसी रिचर्स' में 'विजिटिंग प्रोफेसर' अजीत मजूमदार के अनुसार, "सातवीं योजना के लक्ष्यों और विकास के संदर्भ में प्रधानमंत्री के तकनीकी-व्यवस्थापकीय नजरिये के बीच कोई संबंध नहीं है। देखा जाये तो भारतीय योजना का संकट, प्राथमिकता का संकट है। नेहरू के समय में योजना आयोग के सदस्य रहे तरलोक सिंह का कहना है कि वर्तमान शासन की नजर से आम गरीब ओझल हो गया है। दूसरे लोग भी राजीव गांधी को उभरते धनियों और अर्द्ध संपन्न मध्यवर्ग का हमदर्द मानते हैं। लंदन के कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोग की टिकाऊ वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखने वाले ऐसे लोगों की जनसंख्या मात्र ८ करोड़ है। जो भारतीय अर्थशास्त्री ज्यादा आशावादी हैं, वे इस संख्या को १२१ करोड़ तक आंकते हैं। इनमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार मनटेक सिंह अहलूवालिया व 'फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री' के प्रवक्ता डा० एच० पई पनंदिकर शामिल हैं। कुछ भी हो, सरकार जिस वर्ग की खैरख्वाह है, उस वर्ग में भारत का आम गरीब नहीं है जो कि नेहरू की नजर में हमेशा रहा है।

योजनाबद्ध विकास के प्रणेता: पं० नेहरू

पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में योजना के महत्व को याद करते हुए तरलोक सिंह बताते हैं, "यहां तक कि मरने के १७ दिन पहले भी जवांहर लाल नेहरू ने योजना आयोग की एक बैठक की अध्यक्षता की थी। अब हालत यह है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग में केवल आखिरी बात कहने जाते हैं। नेहरूजी के समय में आयोग को नीतियां तय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। आयोग केन्द्र की इच्छाओं को पूरा करने का एक औजार मात्र नहीं था। यदि भूमि सुधार का मामला हो, तो आयोग पहले राज्यों के साथ उस पर चर्चा करता था और फिर केन्द्र को नीति संबंधी सलाह देता था। सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं में भी सरकार की मदद करता था। पचास और साठ के दशक में गांवों में पंचायत राज को प्रोत्साहित करने में भी आयोग की मुख्य भूमिका रही थी। ठीक इसके विपरीत राजीव गांधी की नयी शिक्षा नीति में योजना आयोग की कोई खास भूमिका नहीं रही।

स्वायत्तता एक सपना: योजना आयोग की स्वायत्तता आज सपना बनकर रह गयी है। एक काबीना मंत्री के आयोग के उपाध्यक्ष बन जाने से केन्द्रीय मंत्रियों पर आयोग का प्रभाव कम हो गया है। तरलोक सिंह कहते हैं, "पहले कोई भी महत्वपूर्ण योजना तब तक कैबिनेट में नहीं भेजी जाती थी, जब तक कि योजना आयोग उसे स्वीकृति न दे दे। अब ऐसा नहीं होता। अब बहुधा आयोग के उपाध्यक्ष की रस्मी राय के साथ परियोजना सीधे कैबिनेट में भेज दी जाती है। अतः इन परिस्थितियों में आयोग के परियोजना मूल्यांकन विभाग का कोई मतलब नहीं रहा। साथ ही उपाध्यक्ष-पद का भी अवमूल्यन हुआ है।

अजीत मजूमदार के अनुसार, "उपाध्यक्ष एक अच्छा चिंतक होना चाहिए। उसमें विकास के आधारभूत सिद्धान्तों की भली भांति समझ होनी चाहिए। उसे मुख्यमंत्रियों का भरोसा प्राप्त होना चाहिए।" इससे तरलोक सिंह भी सहमत हैं। वह कहते हैं, "उपाध्यक्ष को अपना पूरा समय आयोग को देना होगा। यह असंभव है कि कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में राजनीतिक जिम्मेदारियां भी निभाये और योजनाओं का बारीकी से निजी तौर पर और अपने साथियों के साथ अध्ययन करे। आयोग के उपाध्यक्ष को ज्यादा-से-ज्यादा समय योजनाओं में सामंजस्य बिठाने में खर्च करना होता है। इसके अलावा राज्यों से सहयोग बनाये रखने, वर्तमान आर्थिक नीतियों की दिशाओं की समीक्षा और भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए भी काफी समय उसे देना पड़ता है।"

तरलोक सिंह का नजरिया पहली योजना कमेटी के आदर्शों को दर्शाता है। स्वतंत्रता से पूर्व १९३७-३८ में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनायी थी। इस समिति के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे। अतः आजाद भारत में योजना आयोग की स्थापना पहले से जारी राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित करना था। इस योजनाबद्ध विकास को पर्याप्त राष्ट्रीय समर्थन भी मिला।

योजना आयोग बनाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसकी आलोचना भी कम नहीं हुई। तत्कालीन वित्तमंत्री जान मथाई ने इस आयोग की स्थापना के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। उनके अनुसार आयोग कैबिनेट के अंदर कैबिनेट होगा, जबकि योजनाबद्ध विकास के अन्य आलोचकों के अनुसार आयोग सरकार के ऊपर सरकार है। बहरहाल आलोचना से आयोग का कुछ नुकसान नहीं हुआ। वास्तव में यह आयोग को मिली स्वायत्तता की प्रशंसा थी।

साहसी कदम : गुलजारी लाल नंदा आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने। लेकिन ज्योंही आयोग ने गति पकड़ी, नेहरू ने वी०टी० कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बना दिया। तीसरे योजना आयोग में मुख्य भूमिका पी०सी० महालानोबिस की रही जिनका आयोग के एक सदस्य की हैसियत से अमूल्य योगदान था। महालानोबिस के समय में ही देश में उपलब्ध स्रोत और जरूरतों के अनुसार दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करने की दिशा में सोचना शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में आयोग ने साहसी कदम उठाये। हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों की नजर में वे कदम हकीकत से परे थे।

वी०टी० कृष्णमाचारी के बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बी०डी० गाडगिल उपाध्यक्ष बने। उन्होंने योजनाओं पर पहले ही बहुत काम किया था, पर गाडगिल ने योजना आयोग के लिए एक ठोस नीति बनायी, लेकिन उनके सारे प्रयास बेकार चले गये। उन्हें इंदिरा गांधी से कोई राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। श्रीमती गांधी ने अशोक मेहता को उपाध्यक्ष बनाया। वह भारत के राजनीतिक अर्थशास्त्र को भली भांति समझने वाले आयोग के आखिरी व्यक्ति थे और प्रधानमंत्री पर उनका असर था। उनके बाद पी०एन० हक्सर और डी०पी० धर आये जो श्रीमती गांधी के विश्वासपात्र थे।

१९७७ में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एल०के० लकड़वाला को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। जाने-माने अर्थशास्त्री श्री लकड़वाला ने आयोग की खोई हुई स्वायत्तता और प्रतिष्ठा वापस प्राप्त की। ऐसा मोरारजी द्वारा विशेष रुचि लेने और तत्कालीन वित्तमंत्री चरण सिंह द्वारा हस्तक्षेप न करने के कारण हो सका। जनता सरकार के जाने के बाद श्रीमती गांधी सत्ता में आयीं, तो उन्होंने योजना आयोग को एक प्रकार से भुला दिया। उनके पुत्र राजीव गांधी भी आयोग की अनदेखी कर रहे हैं।

बढ़ती दूरी : आयोग और प्रधानमंत्री के बीच बढ़ती दूरी के कई प्रमाण हैं। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री बी०एम० भाटिया के अनुसार, "आयोग का पूरी तरह से नौकरशाहीकरण हो गया है। मनमोहन सिंह अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन एक नीति-निर्माता के बजाय उन्होंने एक नौकरशाह की तरह काम किया। उन्होंने बहुत कम आजादी दिखायी और बिना मौलिक प्रयासों तथा आजादी के आयोग को सक्रिय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है।" इसमें २४ विभाग और कई समितियां हैं। कुछ विभागों में सलाहकार हैं, कुछ में संयुक्त सलाहकार, कुछ में उप सलाहकार और कुछ में ये तीनों हैं। भावी योजनाएं तैयार करने वाले एक छोटे विभाग में दो संयुक्त सलाहकार, चार उप सलाहकार, १२ वरिष्ठ शोध सलाहकार और १२ शोध सलाहकार हैं। लेकिन इनका योगदान न के बराबर है।

उपेक्षा की शुरुआत : श्रीमती गांधी

बिलकुल उपेक्षा : राजीव गांधी

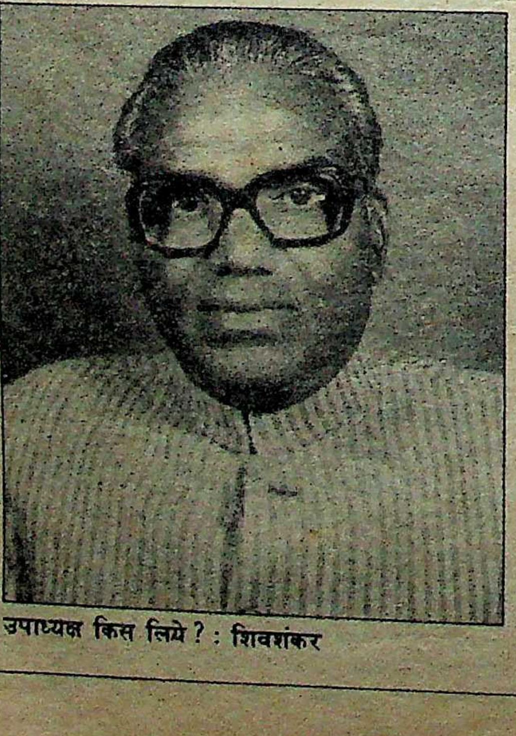
उपाध्यक्ष किस लिये ? : शिवशंकर

जनता पार्टी के कार्यकाल में योजना आयोग के सदस्य रह चुके गांधीवादी अर्थशास्त्री जे०डी० सेठी कहते हैं, "योजना आयोग की भूमिका प्रधानमंत्री तय करते हैं। यदि प्रधानमंत्री आयोग को आर्थिक योजनाओं और विकास का केन्द्र बिन्दु बनाना चाहते हैं, तो उन्हें उसे बहुत ज्यादा महत्व देना होगा। यदि वह इसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो फिर आयोग बेकार है। बी०एम० भाटिया भी इसी विचार के हैं, "प्रधानमंत्री को योजनाएं निर्धारित करने का काम आयोग पर छोड़ देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कुछ सीमा तक ऐसा किया था, लेकिन आज यह बिलकुल नहीं किया जा रहा है।"

अजीत मजूमदार, राजीव गांधी के काल में योजना आयोग की अनदेखी के दो कारण मानते हैं। पहला, योजना आयोग से बगैर सलाह-मशविरा किये आर्थिक नीति में परिवर्तन किये गये। उदाहरण के लिए उदारीकरण की नीति आयोग ने नहीं बनायी थी, बल्कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय में तैयार हुई। यदि देखा जाये तो उदारीकरण की नीति सातवीं योजना से मेल नहीं खाती। दूसरे, प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक हितों के लिए सातवीं योजना के लक्ष्यों की बिना चिंता किये राज्यों को बड़ी संख्या में कर्ज और अनुदान बांट रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आयोग की सलाह के बिना पीने के पानी, अशिक्षा और दूर संचार के लिए तकनीकी मिशन स्थापित कर दिये हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार किया कि आज की तरह वह पहले कभी निराश नहीं हुए थे। एक सलाहकार जिसने अपना नाम देने से मना किया, कहा, "हम कागजी कार्यवाही के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और वह भी औसत दर्जे की है। इसी तरह आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का स्तर भी आयोग में गिरता जा रहा है।"

बी०एम० भाटिया तर्क देते हैं कि कृषि में आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाने के जोरदार प्रयास और उत्पादन में वृद्धि की योजनाओं के अलावा भारत में किसी भी योजना का कोई मतलब नहीं है। स्व० प्रोफेसर राज कृष्णा व्यंग्य भरे स्वर में कहा करते थे, "हर भारतीय योजना पहली योजना का ही एक रूप है। आखिर ऐसी नीति को जारी रखने से क्या फायदा हो सकता है, जिसके तहत कोई सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन न हो सका हो। वास्तव में पहली दो योजनाओं को छोड़कर बाकी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की रपटों की खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि राजीव गांधी को योजना आयोग के प्रमुख पद के लिए कोई अच्छा अर्थशास्त्री नहीं मिला। लेकिन आज जरूरत अच्छे अर्थशास्त्रियों से ज्यादा प्रधानमंत्री और सरकार की प्रतिबद्धता की है। क्या वह वैज्ञानिक ढंग से तैयार योजनाओं पर अमल करने और योजना आयोग को विकास योजनाएं बनाने के अधिकार देने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो योजना आयोग निश्चित रूप से महत्वहीन होने के दौर में है।

—नीरज कौशल

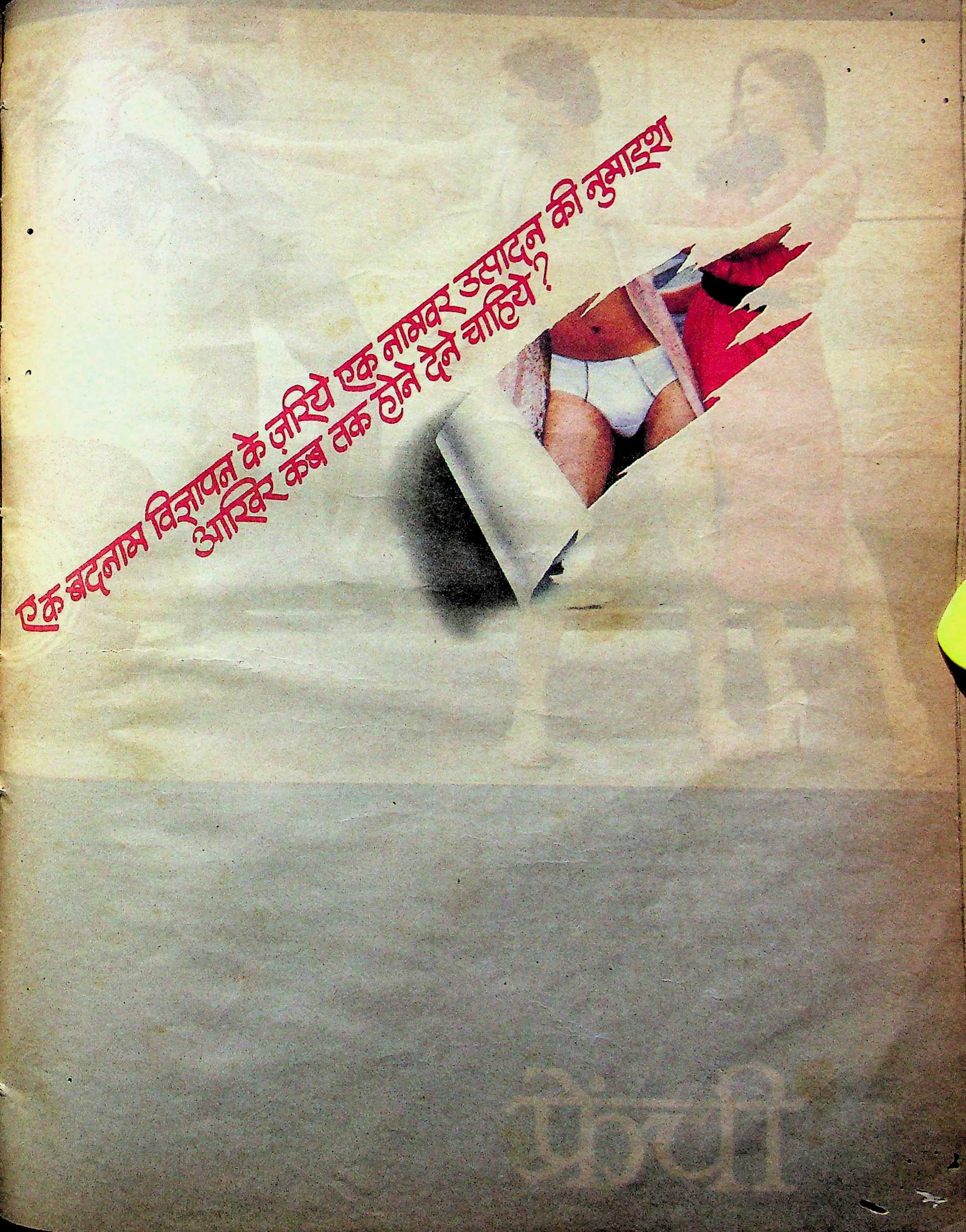
एक बदनाम विज्ञापन के ज़रिये एक नामवर उत्पादन की नुमाइश
आखिर कब तक होने देने चाहिये?
फ्रेंची

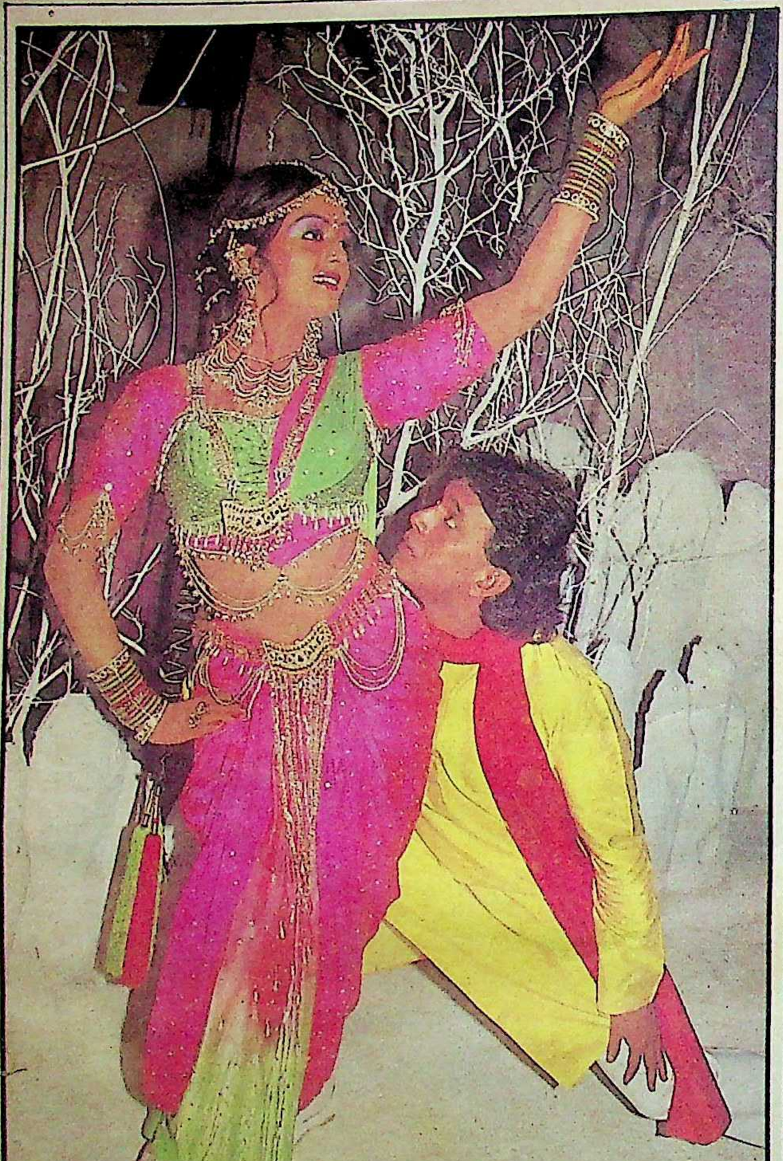

मिथुन चक्रवर्ती और भानुप्रिया

छाया: दुर्गा प्रसाद

दोस्त दोस्त ना रहा...

मिथुन चक्रवर्ती अब श्रीदेवी से इतना अधिक नाराज हैं कि उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। 'मि० इंडिया' और 'नगीना' की अपार सफलता ने श्रीदेवी के दिमाग को इतना चढ़ा दिया कि १९८६ के अपने 'अंतरतम स्टार दोस्त' मिथुन चक्रवर्ती को इस कदर दरकिनार कर बैठीं कि १९८७ में मिथुन का फिल्म मार्केट ऊपर से एकदम नीचे आ गिरा। मिथुन को विश्वास था कि श्रीदेवी उसे, उसके संकटग्रस्त कैरियर को संभालने में मदद करेंगी, लेकिन श्रीदेवी उसे भूलकर धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टारों के साथ फिल्में साइन करने लगीं। मिथुन का एक दोस्त जब श्रीदेवी को साइन करने पहुंचा तो श्रीदेवी ने उसे मिथुन की जगह धर्मेंद्र या विनोद खन्ना को साइन करने की सलाह दी। अब वह ठहरा दोस्त मिथुन का, फिर गाढ़े दिनों में उबारने में पहल की थी मिथुन ने, इसलिए वह तुरंत भानुप्रिया के घर पहुंचा और श्रीदेवी की जगह उसे साइन कर बंबई आ पहुंचा।

श्रीदेवी के बदले व्यवहार से व्यथित बंगाली बाबू को जैसे उस दोस्त ने आत्मज्ञान दे दिया। अब मिथुन अधिक-से-अधिक फिल्में भानुप्रिया के साथ साइन कर श्रीदेवी को गहरा झटका देने पर जैसे उतारू हो गये हैं और उसका साथ दे रहे हैं, जीतेंद्र, जो मद्रास से किसी ऐसे नये चेहरे की तलाश में जुटे हुए हैं, जिसे श्रीदेवी का विकल्प बनाकर पेश कर सकें। अब मिथुन के हम-दोस्त बन जाने से जीतू का हौसला और भी बढ़ गया है।

अब देखें श्रीदेवी कौन-सा नया मोहरा चलती हैं, अपने कैरियर के वजीर को बचाने के लिए।

सीता की मायूसी

'रामायण' सीरियल के १३ और एपीसोडों को एक्सटेंशन मिल जाने पर जब रामायण-यूनिट जश्न मना रही थी, बेचारी सीता यानी दीपिका मायूसी ओढ़े एक किनारे बैठी थीं। मायूसी का कारण था अपार लोकप्रियता मिलने पर भी फिल्मों में काम न मिलने का असंतोष। सीता की इमेज बन जाने के कारण फिल्म निर्माता उन्हें रोमांटिक भूमिकाएं देने में कतरा रहे थे कि पेड़ के इर्द-गिर्द नायक के साथ गलबहियां डाले नाचती-कूदती सीता को दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। एक फिल्म निर्माता ने उन्हें सलाह दी कि, जनवरी, '८८ में ज्यों ही 'रामायण' सीरियल खतम हो, वह ग्लैमर और एक्शन भरी एक भूमिका निभा डालें और इसकी पब्लिसिटी पहले से कतई न करें। फिल्म हिट हो गयी, तो वह चल निकलेंगी-सुजाता मेहता (प्रतिघात) की तरह, लेकिन इसके लिए उन्हें कम-से-कम कपड़े पहनने पड़ेंगे—आखिर सुजाता ने बीच सड़क पर निर्वस्त्र दृश्य दिया था या नहीं और वही दृश्य उसे 'हिट' बना गया था। (यों सुजाता का कहना है कि यह दृश्य उस पर नहीं, एक एक्स्ट्रा लड़की पर फ़िल्माया गया था।)

दीपिका को उस फिल्म निर्माता की बात इतनी भा गयी कि सीता की इमेज तोड़ने के लिए वह अपना नाम तक बदलने को तैयार हो गयीं। 'रामायण' में गमगीन चेहरे का एक-सा पोज

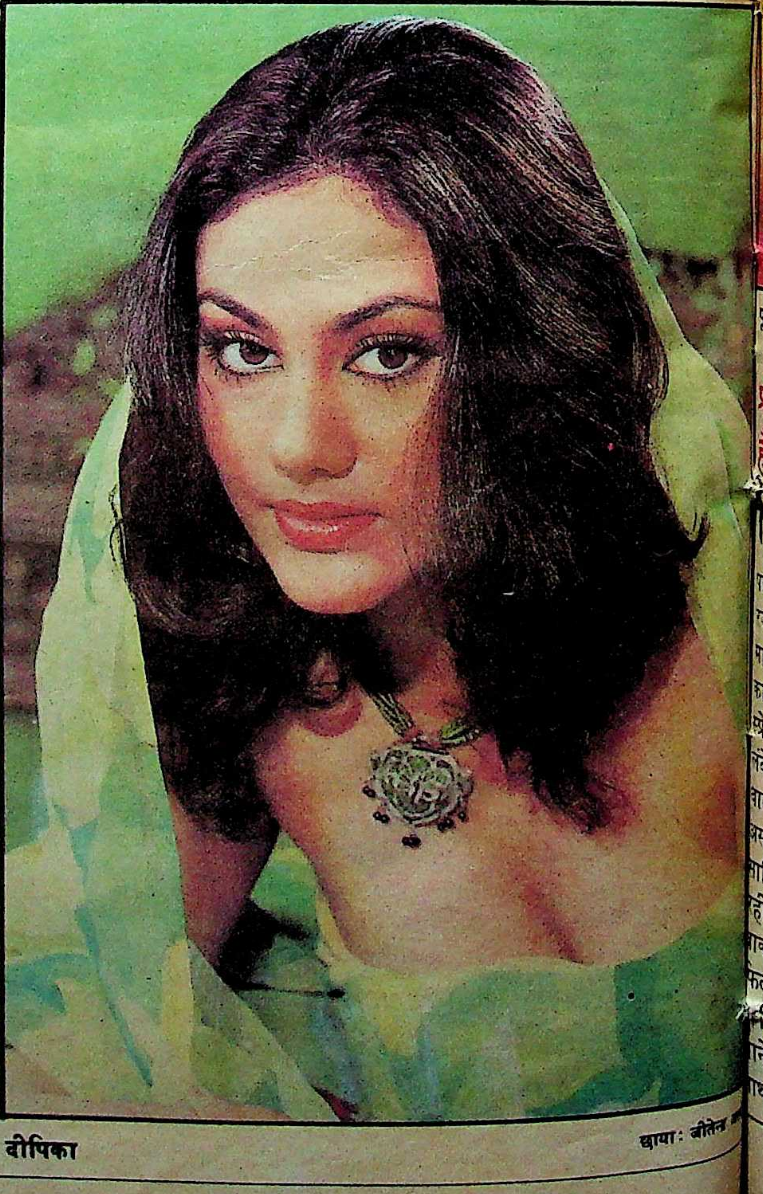

दीपिका

छाया: जीतेन

देते-देते वह इतना उकता गयी थीं कि 'चेंज' के लिए मॉडलिंग भी करने लगी थीं। कभी अकेले तो कभी अपने राम-अरुण गोविल के साथ। साथ ही बड़ी बेसब्री से जनवरी की प्रतीक्षा कर रही थीं कि रामायण खतम हो और धांसू भूमिकाओं वाली फिल्मों में काम शुरू कर सीता की इमेज तोड़ दें, लेकिन अब उन्हें अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा।

बेचारी सीता के दुख को सागर कैसे समझ सकते हैं भला!

पूजा बेदी छाया: जीतेन्द्र आर्य

प्रोतिमा का कहना है!

बिना फिल्मों में एक दृश्य की भी शूटिंग किये अपने पारदर्शी एवं अल्पतम परिधानों, रजनीशी टाइप की उन्मुक्त सेक्स मान्यताओं और बिदासपने के कारण फिल्मी पत्रिकाओं के सेंट्रल स्प्रेड और गाशिप पत्रिकाओं की लंबे अरसे तक 'हाट केक' रहने वाली प्रोतिमा बेदी अपने को असली माने में भारतीय पत्नी साबित करने की कोशिश करती रहीं। इसीलिए पति कबीर से बाकायदे अलग हो जाने, फिर फिल्मी 'खिलंदड़े' आई॰एस॰ जौहर से विवाह कर उनसे भी अलग हो जाने के बावजूद, अपने नाम के साथ 'बेदी' शब्द उन्होंने नहीं हटाया। कबीर बेदी जब विदेशी पत्नी के साथ बंबई आये, तो प्रोतिमा ने न केवल उन्हें अपने साथ ठहराया, बल्कि सौत के साथ ऐसा बहनापा व्यवहार बनाया कि भारतीय पत्नियों की सौत के बारे में कुख्यात विचारधारा ही जैसे ढह गयी, कबीर की विदेशी पत्नी के मन से।

वही प्रोतिमा अब कबीर से बदला लेने पर तुली हुई हैं इन दिनों। कबीर अपनी बेटी पूजा बेदी को फिल्म में लाने के कतई विरुद्ध रहे, लेकिन प्रोतिमा पूजा को मॉडल और अभिनेत्री बना रही हैं, ताकि १६ वर्ष पहले का बदला चुका सकें कबीर से। १६ वर्ष पहले कबीर जिस तरह प्रोतिमा को असहाय छोड़कर परवीन बाबी के साथ रहने उसके फ्लैट पर चले गये थे, उससे प्रोतिमा इतनी मर्माहत हुई कि उसे संभलने में वर्षों लग गये। खालीपन को तोड़ने के लिए उन्होंने ओडेसी नृत्य सीखा, फिर उसका देश-विदेश में प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। लेकिन प्रोतिमा का कहना है—"मेरी बेटी में अभिनेत्री के गुण हैं, तो क्यों नहीं बने वह अभिनेत्री?" लेकिन बिदास प्रोतिमा के मन को भला कौन समझ सकता है, सिवाय औघड़ कबीर बेदी के!

राजा बजाये बाजा...

शाहजहां मुमताज के लिए ताजमहल बनाकर अमर हो गये थे और सुनील दत्त भी अपने छोटे भाई सोमदत्त को हीरो बनाने के लिए ५० लाख रुपए के घाटे से 'मन का मीत' बना कर अपने भ्रातृप्रेम के लिए चर्चित हो गये। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं, जयाप्रदा। अपने भाई राजा को पहले उन्होंने फिल्म निर्माता बना दिया, लेकिन राजा की तमन्ना थी—राजेश खन्ना, अमिताभ बनने की। जयाप्रदा को साइन करने के लिए लाइन लगाने वाले फिल्म निर्माताओं के दफ्तर पहुंच कर खुद को हीरो बनाने के लिए इसरार करते। लेकिन हीरोइन के भाई के नखरे से पहले से ही बेदम फिल्म निर्माता जयाप्रदा के डेटों के लिए उसे बतौर हीरो साइन कर अपनी निर्माण संस्था का बधिया बैठाने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह कई वर्षों से राजा का हीरो बनना टलता रहा।

निर्माता-निर्देशक सावन कुमार टाक को जयाप्रदा के भ्रातृ-दर्द का आभास हुआ, तो वह तुरंत पहुंच गये उनका दर्द दूर करने। जयाप्रदा और टीना मुनीम को लेकर एक फिल्म भी घोषित कर दी। रोमांटिक जोड़ी के लिए राजा के लिए एक नयी लड़की की तलाश कर लाये। कहीं राजा बधिया न बैठा दे, इसलिए रोमांटिक कहानी को थोड़ा अदल-बदल कर त्रिकोणात्मक बना दिया और 'सेफ्टी' के तौर पर सुमीत सहगल को भी साइन कर लिया। अब नायकों के बीच सैंडविच बनी नायिका का कैरियर तो सुरक्षित हो गया, लेकिन फिल्म जब संपादित होकर प्रदर्शित होगी, तो बेचारे राजा के हिस्से कितने दृश्य आयेंगे इसके लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा—बशर्ते जयाप्रदा-टीना मुनीम के साथ जोड़ीदार बनने के लिए राजेश खन्ना न आ जायें और सारे नये सितारों के सीन भी अपने लिए न हथिया लें।

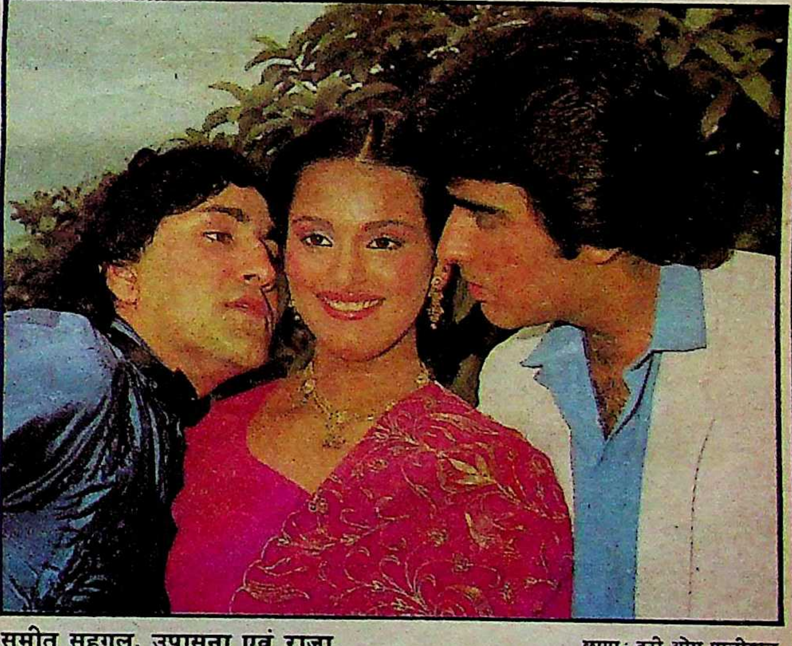

सुमीत सहगल, उपासना एवं राजा छाया: हरी ओम पालीवाल

राम का अंतर्द्वंद्व!

टी॰वी॰ के छोटे-से परदे पर हर रविवार को ५ करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु-दर्शकों को दर्शन देनेवाले भगवान राम उर्फ अरुण गोविल आजकल रावण-अहि रावणों (पीत-पत्रकारों) पर काफी खफा हैं। खफा तो उनकी असली सीता (धर्मपत्नी लेखा गोविल) भी हैं। बकौल राम एक पत्रकार ने उनके और दूरदर्शनी सीता (दीपिका) की दोस्ती को अपने कलंकित हथियार (कलम) से इतने कलुषित और अनर्गल भाषा में इस विकृत ढंग से लिखा कि उन पंक्तियों को पढ़ने से न केवल शर्म से उनकी आंखें झुक गयीं, बल्कि मानसिक रूप से वह कई दिनों तक व्यथित रहे। लेकिन इससे ज्यादा क्षुब्ध वह तब हुए जब वह पत्रकार उनकी पत्नी लेखा पर भी छींटे उछालने से बाज नहीं आया।

"आप तो हम दोनों को जानते हैं। एक-दूसरे के लिए हम पति-पत्नी दुनिया की सारी दौलत तो क्या अपनी जिंदगी तक न्योछावर कर सकते हैं। हमारे बारे में इतनी गंदी बातें लिखते इन पीत-पत्रकारों के हाथ क्यों नहीं कांपते? भगवान राम और शंकर (असली) उन्हें जरूर दंड देंगे।" लेखा गोविल ने जब 'माया' से ये शब्द कहे तो टी॰वी॰ के राम के चेहरे पर चिरपरिचित रामायणी मुस्कान दमकती रही।

—अखबारी लाल

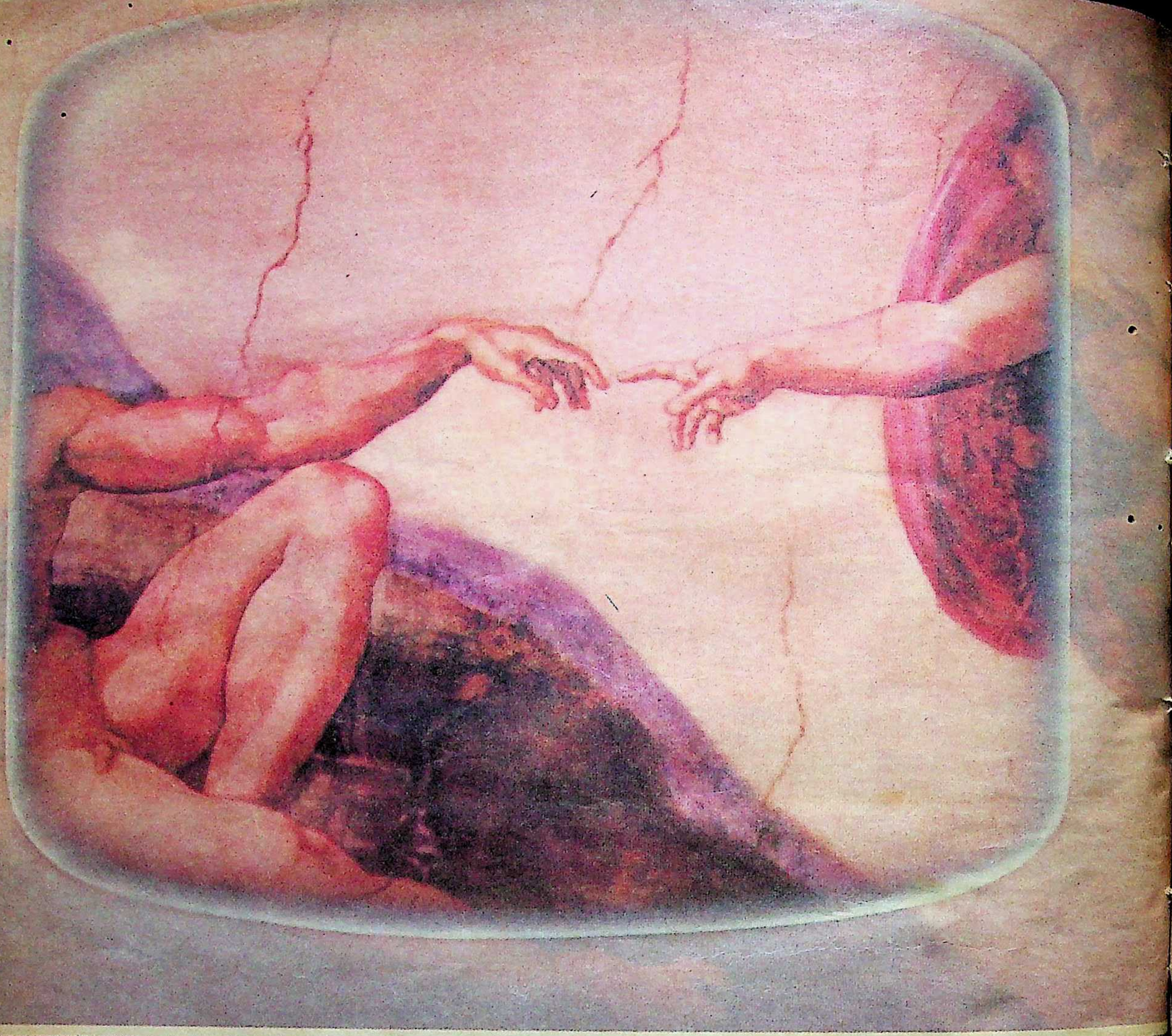

माईकलएंजलो की चित्रकारी। बेलटेक ने क्या खूब निखारी।

CH 4
OFF TIMER

माईकलएंजलो को यह ख़ूबसूरत पेंटिंग बनाते वक्त गुमान भी नहीं रहा होगा कि, आज टेलीविज़न की आधुनिकतम ख़ूबियों के ज़रिये उसमें इतनी जान डाली जा सकती है। बेलटेक के इस कमाल पर माईकलएंजलो भी रह जाता हैरान!

बेलटेक पेश करते हैं बी टी के-777 अतिआधुनिक और नयी-नयी ख़ूबियों के साथ—

- साफ तस्वीर
- देखने से आँखों पर बिल्कुल जोर नहीं
- ऑन स्क्रीन डिस्प्ले—चैनल, वॉल्यूम, कलर और चमक (ब्राइटनैस)
- ऑफ टाइमर
- ऑटो सर्च ट्यूनिंग
- बर्स्ट क्लीनिंग सर्किट
- फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल

BELTEK

तस्वीर जो खुद कहे कहानी

CLARION D 184 HIN

अब गुब्बारे करेंगे दिल का इलाज

भारत में गंभीरतम तथा जानलेवा बीमारियों में तीसरा स्थान दिल का है और एक दशक के भीतर यह पहले स्थान पर पहुंच जायेगा। महानगरों से बढ़कर अब गांवों तक तथा वृद्धों-अधेड़ व्यक्तियों से लेकर अब शिशुओं तक को अपना शिकार बनानेवाले इस हृदय रोग से निजात पाने के लिए समूचे विश्व में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं में से एक है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी अर्थात बैलून पद्धति। बैलून पद्धति दूसरी सभी विधियों से अपेक्षाकृत काफी सस्ती, सरल एवं आरामदेह है। प्रस्तुत है, भारतीय स्वास्थ्य संगठन के महासचिव एवं प्रख्यात चिकित्सक डा० ईश्वर प्रसाद गिल्डा द्वारा इसका विशेष विवरण:

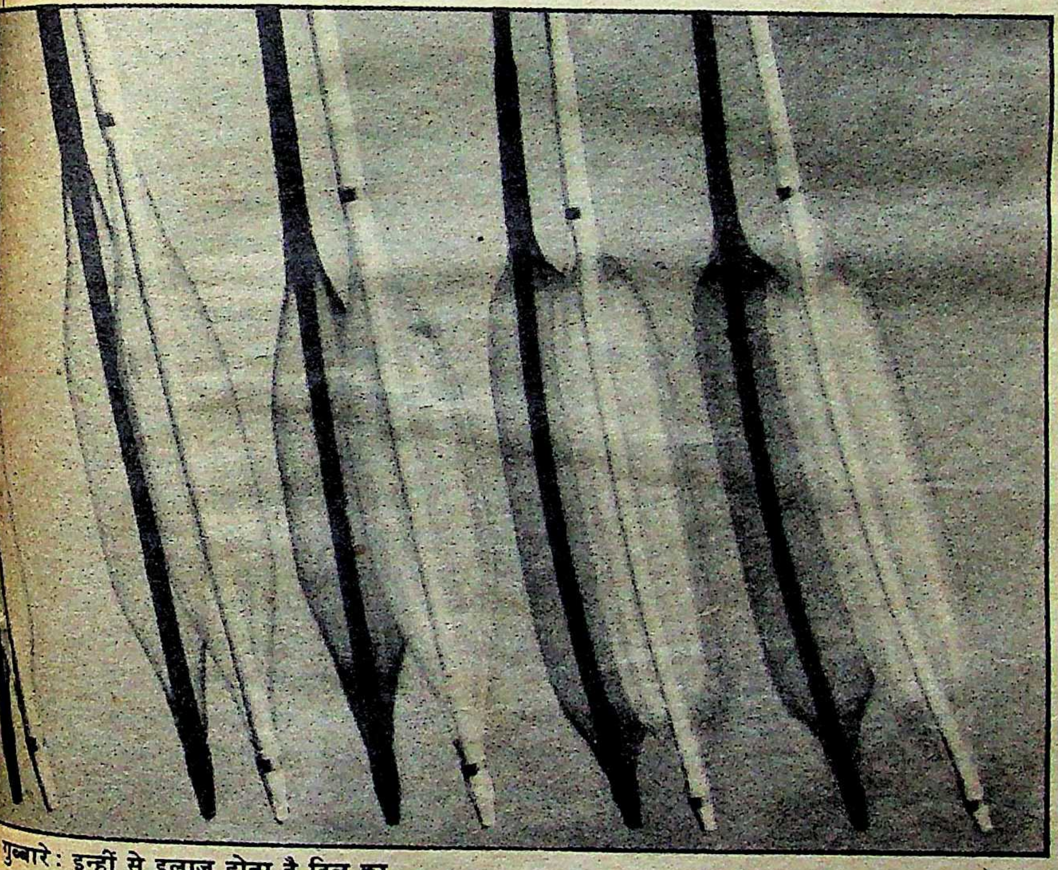

गुब्बारे: इन्हीं से इलाज होता है दिल का

दिल से बढ़कर नाजुक चीज इस दुनिया में शायद कोई और नहीं है, तभी किसी रूपसी को देखते ही दिल नाम की यह चीज जो धड़कना शुरू कर देती है, तो प्रेमी-प्रेमिका के सामने (अब तो प्रेमिका एवं प्रेमी अधेड़ उम्र के भी होने लगे हैं) सिवा आहें भरने के कुछ और नहीं बचता। लेकिन अब तो यही दिल कुछ इतना और अधिक नाजुक हो गया है कि सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और धड़कना बंद कर देता है। यों तो प्रकृति ने इसे इस ढंग से सुरक्षा अस्थि कवच प्रदान किया है कि बाहरी आघात का असर उस तक नहीं पहुंच पाता। 'घर को आग लग गयी घर के चिराग से' कहावत इस दिल के साथ लागू होती है, बाहरी आघात के बजाय अंदरूनी (मानसिक) आघात ही इसका दुश्मन बन जाता है।

अमरीका तथा दूसरे यूरोपीय देशों में जहां हृदय रोग नंबर एक 'मैन किलर डिजीज' माना जाता है, भारत में अभी इसका स्थान तीसरा है। लेकिन जिस तरह हृदय रोग अब अधेड़ों-वृद्धों के साथ-साथ किशोरों और शिशुओं के आयु समूहों तथा महानगरों की तनावभरी जिंदगी के दायरे को तोड़कर अपना मृत्यु-पंख गांवों-कस्बों तक फैलाता जा रहा है, उसे देखते हुए कुछ ही वर्षों के भीतर अगर यह जानलेवा नंबर एक रोग बन जाये, तो कोई अचंभा नहीं।

हृदय-रोग पर नियंत्रण पाने के लिए समूचे विश्व में नये-नये रामबाण इलाज के शोध पर काम चल रहा है और इलाज के व्यय को नियंत्रित करने तथा सस्ती चिकित्सा विधि तलाशने का मुहीम भी जारी है। हाल के वर्षों में पांच नयी चिकित्सा पद्धतियां ईजाद हुई हैं—१. वाल्वोप्लास्टी, २. कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ३. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ४. लेसर किरणों से कोरोनरी आर्टरी रोगों का इलाज तथा ५. इंप्लांटेबल डिफिब्रीलेटर।

'इंप्लांटेबल डिफिब्रीलेटर': अचानक हृदय गति रुक जाने पर उसे पुनः झटका देकर क्रियाशील बनाने का काम करता है, इसके पहले बिजली से झटका देकर दिल को कार्यशील बनाने की कोशिश की जाती थी। लगभग ८० हजार रुपए कीमत का डिफिब्रीलेटर मरीज के वक्ष से लगा दिया जाता है। स्थायी हृदय रोग का शिकार मरीज इसे खरीद कर अपने पास रख सकता है। हृदय धमनियों के रोगों को दूर कर हृदय को क्रियाशील बनाने के लिए लेसर किरणों से कोरोनरी आर्टरी का इलाज किया जा सकता है। लेसर किरणों के दुष्परिणामों को रोकने के लिए सटीक उपाय हासिल न हो पाने के कारण इसका उपयोग गंभीरतम स्थितियों में ही किया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (जिसे एम०आर०आई० पद्धति भी कहा जाता है) का उपयोग मस्तिष्क, प्लीहा, मूत्र-पिंड, यकृत आदि विशिष्ट रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ढाई करोड़ रुपए लागत की यह मशीन अमरीका के सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही है।

उपरोक्त तीनों चिकित्सा पद्धतियां जहां काफी खर्चीली हैं, वहीं भारतीय अस्पतालों में उन्हें पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी तथा वाल्वोप्लास्टी इनकी अपेक्षा ज्यादा सरल तथा सस्ती हैं और भारत में इसकी शुरुआत यद्यपि एक-आध अस्पतालों में हो चुकी है, लेकिन आगामी कुछ वर्षों में कई बड़े शहरों में यह चिकित्सा पद्धति उपलब्ध होने लगेगी। ये दोनों पद्धतियां बैलून अर्थात विशेष रूप से तैयार किये गये गुब्बारों द्वारा की जाती हैं।

हृदय का कार्य: इस चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा करने के पहले दिल के बारे में थोड़ी चर्चा आवश्यक है। हृदय प्रति मिनट ७०-७५ बार (एक

वर्ष में ४ करोड़ से अधिक बार) धड़कता है। दिल की धड़कन के साथ रक्त संचार के लिए दो पंप काम करते हैं—हर धड़कन के साथ दोनों पंप ७०-७० मिली० खून पंप करते हैं। यानी एक वर्ष में ५५-६० लाख लीटर खून हृदय से पंप होता है। हृदय के दायें हिस्से में पूरे शरीर से अशुद्ध खून आता है जिसे शुद्धीकरण के लिए फेफड़ों में पंप करता है। हृदय का बायां हिस्सा फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है और मुख्य धमनियों के जरिये पंप करके शरीर की कई शिराओं को तथा लाखों सूक्ष्म शिराओं से उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के किसी भी भाग का (अवयव का) जिंदा रहना शुद्ध रक्त-संचार पर ही निर्भर करता है। इस तरह हृदय रक्त-संचार के जरिये शरीर के प्रत्येक पेशी को जीवनावश्यक खाद्य पहुंचाता है और पेशियों से 'वेस्ट प्राडक्ट्स' को फेफड़ों एवं मूत्र-पिंड में पहुंचाता है। इस कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए हृदय को भी जीवनावश्यक खाद्य की जरूरत पड़ती है, जिसमें आक्सीजन एवं ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसकी आपूर्ति विशिष्ट धमनियों के माध्यम से होती है। इसे हृद् धमनी (कोरोनरी आर्टरी) कहते हैं। उम्र के उतार के साथ ही इन धमनियों में धीरे-धीरे चर्बी जमा (अथेरोस्केलेरोसिस) होना शुरू हो जाती है। इससे धमनियों में रुकावट पैदा होने से वहां रक्त-प्रवाह अनियमित होने लगता है। अथेरोस्केलेरोसिस के कारण सीने में दर्द (अंजाइनापेक्टोरिस) होने लगता है। धमनियों में रुकावट ज्यादा होने पर कभी-कभी धमनियां स्वतः बंद हो जाती हैं और हृदय को होनेवाली रक्त-आपूर्ति बंद हो जाती है। इससे दिल का दौरा (आयोकार्डियल इन्फारक्शन) पड़ जाता है। धूम्रपान, अधिक चर्बीयुक्त खाद्य, कम व्यायाम, चिंता, तनाव, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि कारणों से अथेरोस्केलेरोसिस की शिकायत होती है। यह शिकायत महिलाओं में गर्भनिरोधक गोलियों एवं धूम्रपान के कारण भी हो सकती है।

अंजाइना का इलाज सार्बिट्रेट निफेडीफीन आदि दवाओं से किया जाता है जो अवरुद्ध या बंद धमनियों को खोलने में मदद करती हैं। ज्यादा प्रभाव में होने पर कोरोनरी बायपास आपरेशन का सहारा लेना पड़ता हैं। हाल ही में कोरोनरी बैलून एंजियोप्लास्टी पद्धति से उपचार शुरू हुआ है।

बैलून पद्धति : बैलून चिकित्सा पद्धति एक क्षण के लिए आपको चौंका सकती है कि रबर-प्लास्टिक से बना १२ मिमी० लंबा, २ से ३ मिमी० चौड़ा यह गुब्बारा किस तरह बंद पड़ी या अवरुद्ध धमनियों में प्रवाह पुनः जारी कर सकता है। इस गुब्बारे को एक ट्यूब के साथ गाइडवायर की सहायता से रोगी की फिमोरल आर्टरी (बाजुओं की ब्रोकिअल आर्टरी) से होते हुए हृदय तक पहुंचाया जाता है, फिर इन्हें उन वाल्वों या धमनियों के भीतर से निकाला जाता है जो किन्हीं कारणवश अवरुद्ध या बंद हो चुके होते हैं और उन्हें खोलना जरूरी होता है। बंद या अवरुद्ध वाल्व या धमनी के बीच इन गुब्बारों के पहुंच जाने पर उनमें हवा भरी जारी है। गुब्बारों के फूल जाने पर बंद या अवरुद्ध वाल्व अथवा धमनी भी फैलने लगती है। बैलून को वाल्व के भीतर प्रवेश कराने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए अब कंप्यूटराइज्ड पद्धति भी अपनायी जाने लगी है, जिससे इसकी सारी विधि कंप्यूटर टी०वी० पर दिखलायी पड़ने लगती है। इससे पता चलता है कि गुब्बारा कहां-कहां से होकर गुजर रहा है और अवरुद्ध या बंद वाल्व या धमनी पर, गुब्बारे को फुलाते समय क्या प्रतिक्रिया हो रही है।

बैलून पद्धति की शुरुआत प्रारंभ में स्विट्जरलैंड के हृदय विशेषज्ञ डा० एंड्रयूज गुत्जिक ने की थी। बाद में मिलवाकी (अमरीका) स्थित सेंट ल्यूकास अस्पताल में स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ डा० गेराल्ड डोरास ने उनके मार्गदर्शन में एंजियोप्लास्टी का प्रशिक्षण लिया। स्त्री रोगों की चिकित्सा करते-करते डा० डोरास की रुचि अचानक हृदय रोग का अध्ययन करने में हुई और उन्होंने इसकी विशेषज्ञता टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट (अमरीका) में हृदय रोग विशेषज्ञ डा० वीरेंद्र माथुर (नान रेजिडेंट इंडियन) के निर्देशन में आवश्यक प्रशिक्षण-कार्य कर प्राप्त की।

बैलून
चिकित्सा पद्धति
एक क्षण के लिए आपको चौंका
सकती है कि रबर-प्लास्टिक
से बना १२ मिमी० लंबा,
२ से ३ मिमी० चौड़ा यह गुब्बारा
किस तरह बंद पड़ी या
अवरुद्ध धमनियों में
प्रवाह पुनः जारी कर
सकता है।

इसी वर्ष १६ से २१ फरवरी, '८७ को जब बंबई में सेंट ल्यूकास अस्पताल के सौजन्य से बैलून एंजियोप्लास्टी वर्कशाप का आयोजन हुआ था, तो डा० गेराल्ड डोरास ने न केवल विश्व के विभिन्न देशों से आये ६० हृदय रोग विशेषज्ञों को इस पद्धति के बारे में प्रशिक्षित किया था, बल्कि २० रोगियों की एंजियोप्लास्टी तथा २ रोगियों की अवोर्टिक वाल्वोप्लास्टी पद्धति से चिकित्सा भी की थी। इस इलाज के बाद इन सभी मरीजों को, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था और इस दौरान उन्हें दिल का कोई दौरा नहीं पड़ा।

डा० डोरास ने इस नयी कारगर चिकित्सा पद्धति के बारे में मुझे बतलाया था, "इससे न केवल बिना शल्य चिकित्सा किये हृदय-रोगों का इलाज किया जा सकता है, बल्कि रोगी को दूसरे ही दिन छुट्टी दे दी जा सकती है। इसमें न तो हृदय को खोलने (ओपेन हार्ट सर्जरी) की जरूरत पड़ती है और न ही रोगी को एनेस्थीसिया लगाने की। कोरोनरी बायपास सर्जरी के बाद दुष्परिणामों की संभावना कतिपय स्थितियों में हो सकती है, लेकिन बैलून चिकित्सा पद्धति में नहीं, क्योंकि इसमें दिल या शरीर के किसी भी अंग को कोई क्षति नहीं पहुंचने पाती।"

बंबई में सर्वप्रथम बैलून पद्धति की शुरुआत करने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ ३५ वर्षीय डा० सत्यवान शर्मा (अध्यक्ष, हृदय रोग विभाग, नायर अस्पताल, बंबई) ने 'माया' को बतलाया, "बैलून चिकित्सा पद्धति का उपयोग चार प्रकार के हृदय-रोगियों में किया जा सकता है, (क) कोरोनरी आर्टरी (हृदय धमनियों) में रुकावट आने पर, (ख) कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनके वाल्व जन्मजात छोटे छिद्रवाले तथा धमनियां सिकुड़ी हुई होती हैं, (ग) विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण वाल्व क्षतिग्रस्त, अवरुद्ध या बंद हो जाता है, तथा (घ) विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त धमनियां। कोरोनरी आर्टरी में रुकावट ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी द्वारा खोला जा सकता है, लेकिन यह पद्धति अभी अमरीका में ही प्रचलित है। जन्मजात अवरुद्ध या सिकुड़े हुए वाल्व के लिए उपयोग में आने वाले बैलून की लंबाई ३ से ६ सेमी० तथा चौड़ाई १ से २० मिमी० होती है। विभिन्न रोगों से वाल्व तथा धमनियों के क्षतिग्रस्त होने पर बैलून वाल्वोप्लास् तथा शेष अन्य स्थितियों में बैलून तकनीक कार सिद्ध हो सकती है। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों की शुरुआत मैंने नायर अस्पताल में कर दी है और अपेक्षित सफलता भी मिल रही है।"

बैलून चिकित्सा पद्धति की शुरुआत नाय अस्पताल के अलावा दिल्ली में आल इंडिया मेडिक इंस्टीट्यूट व गोविंदबल्लभ पंत अस्पताल त मद्रास में अपोलो अस्पताल में हो चुकी है, लेकिन इ चिकित्सा पद्धति को भारत में पहली बार लाने वा डा० सत्यपाल शर्मा हैं। डा० शर्मा ने रायल प्रि अल्फ्रेड अस्पताल, आस्ट्रेलिया तथा मैसाचुसेट् जनरल हास्पिटल ऐंड चिल्ड्रेंस हास्पिटल, बोस् (अमरीका) में बैलून चिकित्सा पद्धति का ग प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बंबई आने पर डा० श महानगरपालिका संचालित नायर अस्पताल हृदय रोग के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। सित अक्तूबर, १९८६ में ही उन्होंने बैलून तकनीक इलाज की शुरुआत की।

इस तकनीक से रोगी की चिकित्सा में ४ ९० मिनट का समय लगता है तथा यह काफी स भी पड़ता है। ओपेन हार्ट सर्जरी पर जहां १५ से

हजार रुपए का खर्च आता है, वहीं बैलून पद्धति से चिकित्सा में लगभग २,५००. रुपए खर्च आता है। कोरोनरी आर्टरी को खोलने के लिए लगनेवाले बैलून कैथेटर को छोड़कर बाकी सभी पद्धतियों में बैलून सेट (साहित्य के साथ) लगभग २,५०० रुपए का होता है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए पूरे सेट (साहित्य सहित) की कीमत लगभग १३ हजार रुपए है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के अलावा अन्य बैलून तकनीक में वही बैलून दूसरे मरीजों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, बैलून को कीटाणुनाशक रखना बहुत जरूरी होता है। बैलून तकनीक से चिकित्सा के लिए आपरेशन थियेटर या आई०सी०सी०यू० की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए एक अलग कैथ लैब होता है।

सबसे बड़ी समस्या है, बैलून सेट तथा उसके साहित्य के उपलब्ध होने की, क्योंकि इसका ज्यादातर निर्माण अमरीका में होता है और कानूनन अमरीकी कंपनियां अपने देश में इसकी आपूर्ति पूरी होने पर ही बचे हुए सेट दूसरे देशों को निर्यात कर सकती हैं।

बैलून पद्धति से चिकित्सा का विपरीत परिणाम नहीं होता। कभी-कभी बैलून अंदर ही फूट जाता है, लेकिन इससे मरीज को कोई हानि नहीं होती। सिर्फ बैलून कैथेटर का नुकसान होता है और दूसरा उपयोग करना पड़ता है। इस पद्धति से इलाज के दौरान कभी-कभी रक्त चाप में ह्रास तथा हृदय की गति में अवरोध की शिकायत हो सकती है, लेकिन यह प्राणलेवा नहीं साबित होती। ऐसी स्थिति में रोगी को तुरंत आपरेशन थियेटर में ले जाना चाहिए। बैलून तकनीक उन्हीं अस्पतालों में संभव है जहां सुविधा सज्जित कैथलैब के साथ-साथ ओपन हार्ट सर्जरी की भी व्यवस्था हो।

"हमारे देश के अस्पतालों में बैलून तकनीक की समुचित व्यवस्था हो जाने पर हृदय रोग से होनेवाली मौतों की दर गिर जायेगी," डा० सत्यपाल शर्मा ने 'माया' को बतलाया, "साथ ही चिकित्सा के लिए विदेश जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ संपन्न व्यक्ति ही शौकिया जायेंगे।"

फरवरी में हुए बैलून तकनीक वर्कशाप के दौरान मेरी मुलाकात सेंट एलिजाबेथ हास्पिटल (बोस्टन, अमरीका) के कार्डियक कैथेराइजेशन विभाग के संचालक डा० के० रामास्वामी से हुई थी। बैलून तकनीक में शोध करने वाले डा० गुटिंग के निर्देशन में डा० रामास्वामी ने कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (बैलून तकनीक) में शोध तथा अध्ययन कार्य किया था। उनका कहना था, "हृदय धमनियों में होनेवाली रुकावट, दिल-दर्द, असाध्य हो गया एंजाइना तथा दिल के दौरे से रोगी के हृदय की मांसपेशियों की सुरक्षा ओपेन हार्टसर्जरी तथा दूसरी तकनीक से नहीं हो सकती, सिर्फ बैलून पद्धति से ही सुफल परिणामदायक सिद्ध होगी। जन्मजात एवं सिकुड़े हुए वाल्व को खोलने के लिए ३ से ६ सेमी० लंबे तथा १२ से २० मिमी० चौड़े बैलून का उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि सामान्यतया अवरुद्ध हृदय धमनियों को खोलने के लिए १२ मिमी० लंबे एवं ३ मिमी० (कभी-कभी डेढ़ एवं २ मिमी०) चौड़े बैलून का उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा समस्या जन्मजात एवं सिकुड़े हुए वाल्व को खोलने की होती है।"

किस्सा वाल्व का: वाल्व सामान्यतया आमबात संबंधी हृदय रोगों के कारण सिकुड़ जाते हैं। इसके लिए भारत में ज्यादातर ओपेन हार्ट सर्जरी कर वाल्व का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। भारत वाल्व का निर्माण न होने तथा आयात होने के कारण यह इतना अधिक खर्चीला हो जाता है कि वाल्व का प्रत्यारोपण कराना सामान्य रोगी के बस के बाहर की बात होती है।

वाल्व दो प्रकार के होते हैं—१. मेटेलिक (धातु से बने), तथा २. बायोप्रोस्थेसिस (प्राणियों के शरीर से निकाले या उनके अवयवों से बने हुए)। मेटेलिक वाल्व न केवल मंहगा (लगभग ११ हजार रुपए प्रति वाल्व), होता है, बल्कि रक्त स्राव आदि कई कुप्रतिक्रियाएं भी हो जाती हैं। मेटेलिक वाल्व लगाने के बाद एंटीकोग्युलेंट दवाएं (रक्तस्राव निरोधक) ताजिंदगी लेनी पड़ती हैं, और हमेशा चेकअप करवाना पड़ता है। बायोप्रोस्थेसिस वाल्व की कीमत ७-८ हजार रुपए प्रति वाल्व होती है तथा ये दो प्रकार के बने होते हैं—१. गाय, बैल, भैंस के पेटी कार्डियम या सुअर के पोर्सिन एवोर्टिक वाल्व को निकाल कर उनसे बनाये गये वाल्व। ये बनाने में आसान भी हैं और उन्हें अधिक-से-अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है, २. मृत व्यक्ति के शरीर से निकाला हुआ वाल्व। मृत व्यक्ति की मौत के तुरंत बाद उसके वाल्व को निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्यारोपित (हेमोग्राफ्ट) कर दिया जाना चाहिए।

इससे न केवल बिना शल्य चिकित्सा किये हृदय-रोगों का इलाज किया जा सकता है, बल्कि रोगी को दूसरे ही दिन छुट्टी दे दी जा सकती है। इसमें न तो हृदय को खोलने (ओपेन हार्ट सर्जरी) की जरूरत पड़ती है और न ही रोगी को एनेस्थीसिया लगाने की।

मृत व्यक्ति का वाल्व सर्वोत्तम होता है, लेकिन भारत में संभव नहीं, क्योंकि यहां जब तक व्यक्ति का दिमाग और दिल एकदम से काम करना बंद न कर दे, उसे मृत नहीं घोषित किया जा सकता। दिल के पूर्णतया रुक जाने के बाद उसका वाल्व भी सामान्यतया अप्रभावशाली हो जाता है। अमरीका में मस्तिष्क की मौत को ही असली मौत मान लिये जाने के कानून के कारण वहां मृतक के शरीर से तुरंत वाल्व निकाल कर वाल्व बैंक में जमा कर दिये जाते हैं। संप्रति, त्रिवेंद्रम में चित्रा वाल्व का निर्माण हो रहा है और कुछ ही समय में इसका, संतोषजनक परीक्षण के बाद, मरीजों में प्रत्यारोपण शुरू हो जायेगा।

हृदय रोग की चिकित्सा में कलर डाप्लर इकोकार्डियोग्राफी मशीन ने एक क्रांति की शुरुआत की है। तोकियो में इस मशीन का सर्वप्रथम निर्माण करनेवाले डा० चिहीरो कासाई मूलतः इलेक्ट्रानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रानिक्स में पी०एच०डी०) हैं। डा० कासाई ने कलर डाप्लर मशीन की चर्चा चलने पर मुझे बतलाया था, "हृदय रोग विशेषज्ञों एवं सर्जनों के समक्ष हमेशा यह समस्या रही कि मरीज का आपरेशन कब किया जाये, किया जाये या नहीं तथा कार्डियल कैथेटराइजेशन जैसी चिकित्सा पद्धति जिसमें मरीज को जांच के समय काफी तकलीफ होती है, से कैसे छुटकारा मिले या उसे आसान बनाया जाये। यह मशीन हृदय रोगियों की जांच कर आवश्यक निर्देश देती है, जिसमें आपरेशन करने या न करने का संकेत भी शामिल है। मेरे विचार से हर बड़े नगर के अस्पतालों में यह मशीन होनी चाहिए। इससे रोगी की चिकित्सा भी सरल हो जायेगी तथा हृदय रोग विशेषज्ञों—सर्जनों का समय भी बच जायेगा, फिर इससे पता चल जायेगा कि बैलून को किस हिस्से में और किन-किन रास्तों से प्रवेश कराना चाहिए।"

लगभग ३५ लाख रुपए कीमत वाली कलर डाप्लर मशीन का निर्माण सबसे पहले (१९८२) तोकियो में अलोका कंपनी लि० ने किया था, बाद में तोशिबा तथा दूसरी कंपनियों ने शुरू किया। अलोका के भारतीय नाम जैसा लगने की चर्चा चलने पर डा० कासाई ने बतलाया, "मेरे धर्मगुरु, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, का नाम अलोका है। मुझे उनका नाम पसंद था। मैंने इसका अर्थ तलाशा तो एक अर्थ निकला—आलोक अर्थात प्रकाश। १९८२ में निर्मित कलर डाप्लर मशीन में मैंने बाद में काफी परिवर्तन और सुधार किये हैं। अब इससे हृदय वाल्व के रंगीन चित्र निकालने के अलावा रोग निदान से संबंधित बहुत सारे संकेत मिलने लगे हैं, फिर पहले की अपेक्षा यह आकार में बहुत छोटा हो गया तथा कंप्यूटराइज्ड हो जाने के कारण दूसरे सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। इस मशीन का सबसे पहले उपयोग किया था सायतनामा मेडिकल कालेज (जापान) के शल्य चिकित्सा प्रमुख डा० रोजो आमोटो ने जो अब तक ५ हजार से अधिक हृदय रोगियों की इस मशीन से जांच कर चुके हैं। ■

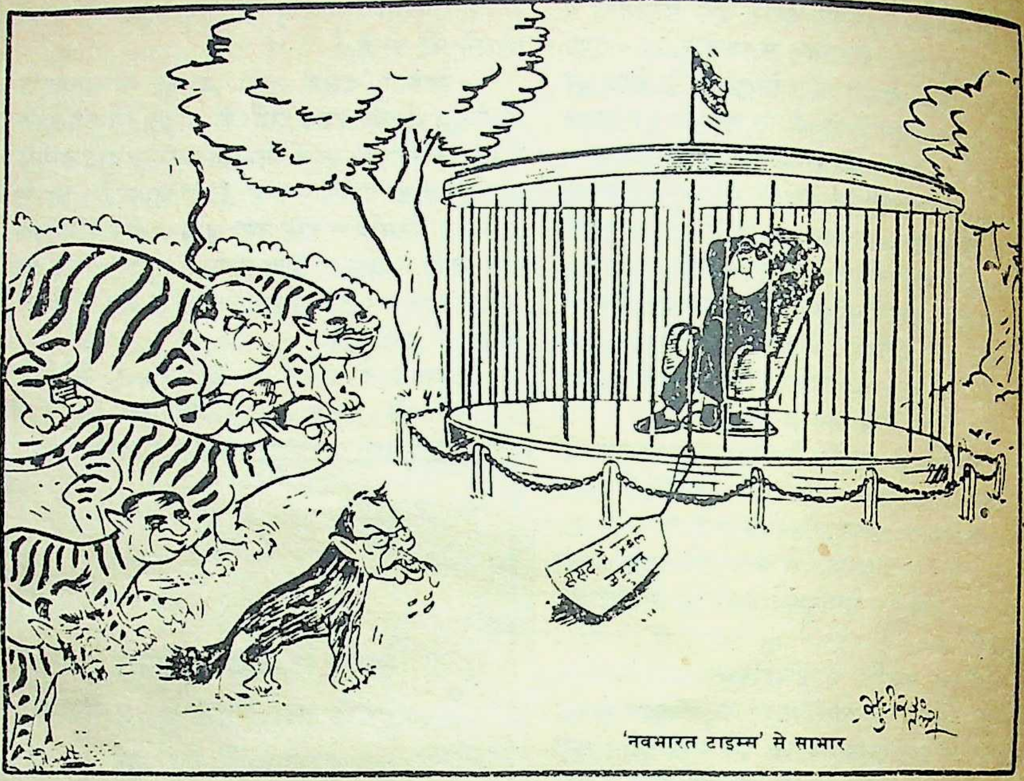

'नवभारत टाइम्स' मे साभार

-सुधीर तैलंग

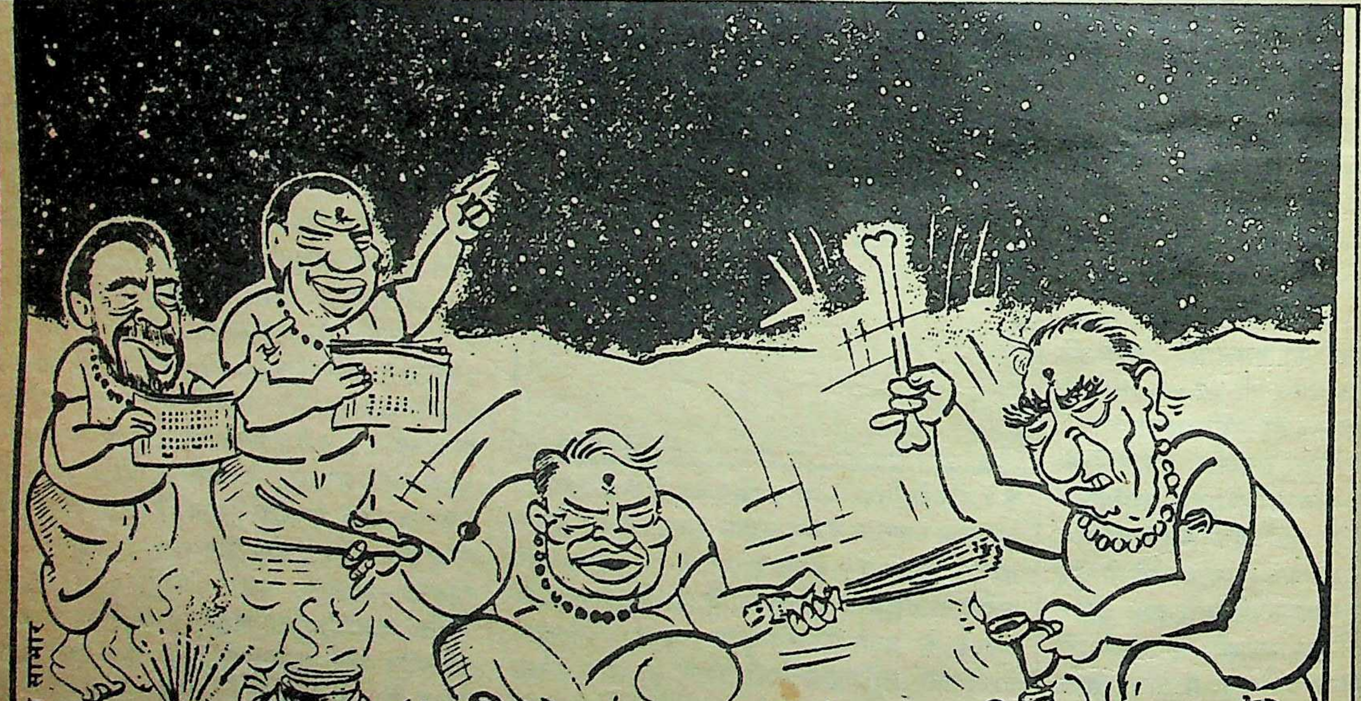
१९७७ जनता प्रयोग
१९७७ प्रयोग दोहराया जाए -पटना रैली

'नवभारत टाइम्स' से साभार

-सुधीर तैलंग

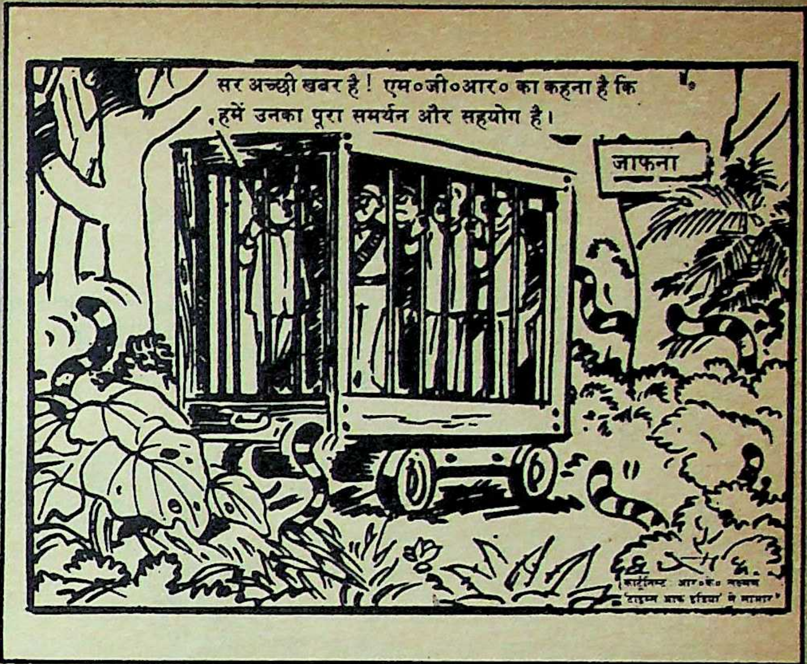
सर अच्छी खबर है! एम०जी०आर० का कहना है कि हमें उनका पूरा समर्थन और सहयोग है।
जाफना

कार्टूनिस्ट: आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' से साभार

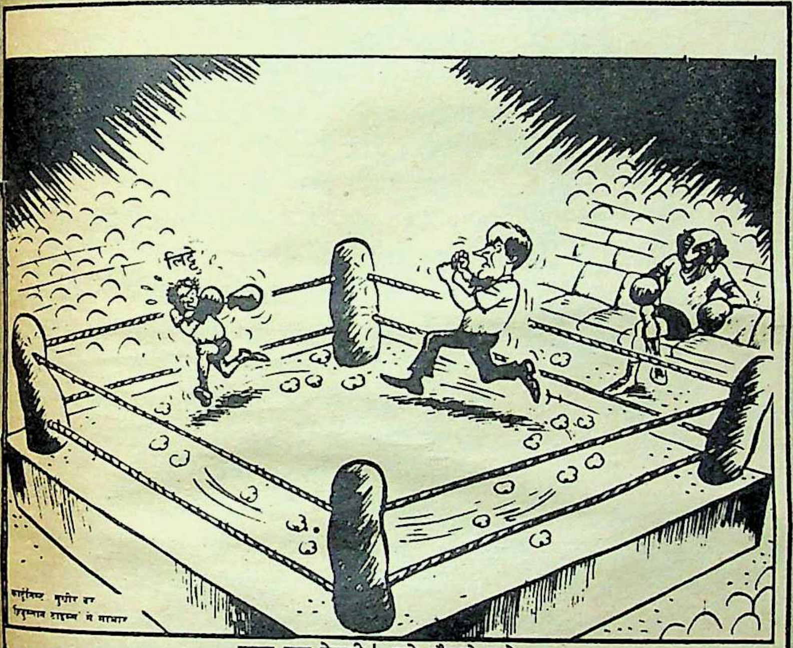

कार्टूनिस्ट: सुधीर दर
'हिन्दुस्तान टाइम्स' से साभार

बहुत खूब रेफरी! उसे दौड़ाते रहो।

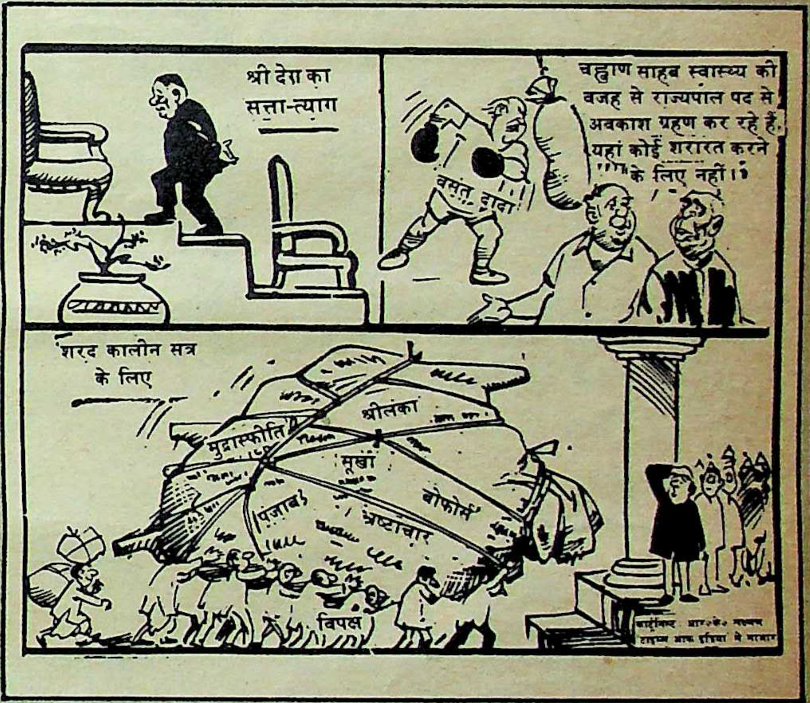
श्री देश का सत्ता-त्याग
चह्वाण साहब स्वास्थ्य की वजह से राज्यपाल पद से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, यहां कोई शरारत करने के लिए नहीं।
वसंत दादा
शरद कालीन सत्र के लिए
मुद्रास्फीति
श्रीलंका
सूखा
पंजाब
बोफोर्स
भ्रष्टाचार
विपक्ष

कार्टूनिस्ट: आर०के० लक्ष्मण
'टाइम्स आफ इंडिया' से साभार

भारतीय व्यापार प्राधिकरण द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय कार्टून और व्यंग्य रेखाचित्र प्रतियोगिता' में १५०० कार्टूनों में प्रथम

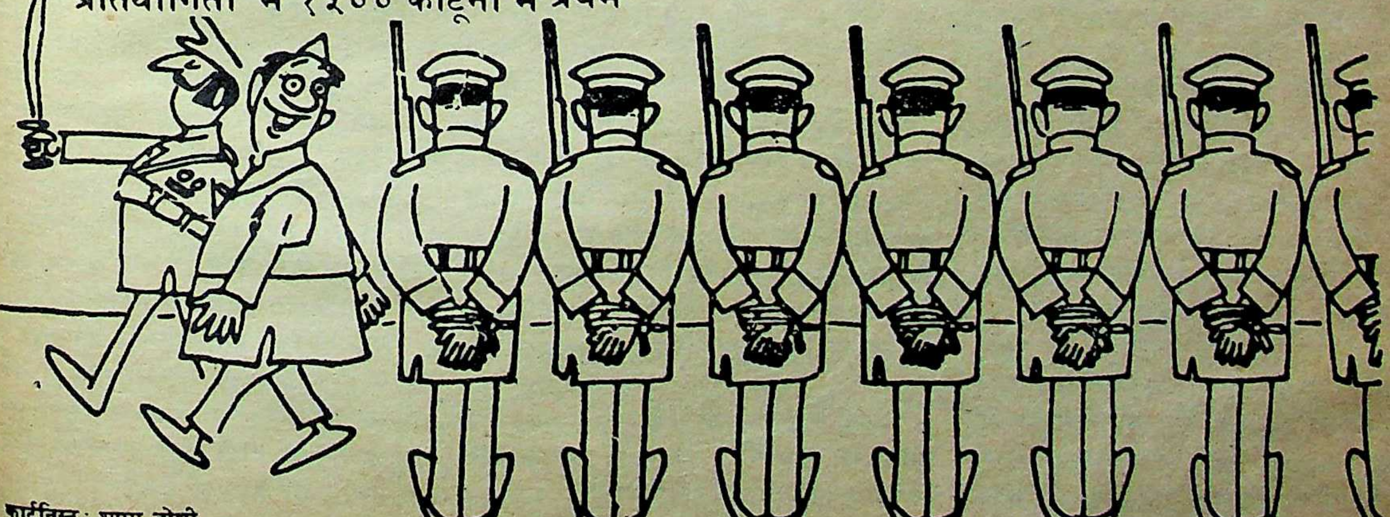

कार्टूनिस्ट: श्याम जोशी

विजय मर्चेंट

हर क्षेत्र में 'नाट बोल्ड' का खिताब पानेवाले ७६ वर्षीय प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय मर्चेन्ट २७ अक्तूबर को हार्ट अटैक के हाथों अचानक तब बोल्ड आउट हो गये, जब दर्शकों की आंख चंडीगढ़ में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे मैच पर गड़ी हुई थी।

भारतीय क्रिकेट के पांच कर्णधारों में एक—विजय मर्चेन्ट हमेशा अपनी 'बेबाकी' और विद्रोही रुख के लिए चर्चित रहे। १९७१ में, चयनकर्ता टीम के सदस्य के रूप में विजय मर्चेन्ट ने जब वेस्टइंडीज जानेवाली भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नवाब मंसूर अली खां पटौदी की जगह अजित वाडेकर को चुना, तो हर किसी ने उनकी आलोचना की, लेकिन जब यही टीम वेस्टइंडीज और आस्ट्रेलिया को हराकर लौटी, तो आलोचक दाद देने में जुट गये। १९६८ में आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जानेवाली भारतीय टीम में एकनाथ सोलकर, अशोक मांकड़ आदि एकदम नये खिलाड़ियों को जिद्द कर शामिल कराने के लिए भी उन्हें तीखी आलोचनाएं सहनी पड़ी थीं।

क्रिकेट यात्रा: प्रख्यात औद्योगिक ठाकरसी घराने में १२ अक्तूबर, १९११ को जन्मे विजय ठाकरसी की रुचि बचपन से ही क्रिकेट में रही। वह स्कूल में जब अपना नाम लिखाने गये, तो अध्यापक द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनके पिता क्या करते हैं, उन्होंने बतलाया, "मर्चेन्ट हैं।" स्कूल अध्यापक ने उनके नाम विजय के आगे ठाकरसी की बजाय मर्चेन्ट लिख दिया। अनजाने में अध्यापक की इस भूल ने उनका नाम ही बदल दिया और वह विजय ठाकरसी की जगह विजय मर्चेन्ट बने, तो अंततः मर्चेन्ट ही बने रहे।

१५ वर्ष की उम्र में, १९२६ में हैरिश शील्ड के फाइनल में १२६ व १०० रन (दोनों बार नाट आउट) बनाकर उन्होंने अपनी बैटिंग का सिक्का ऐसा जमाया कि पी०जे० हिंदू जिमखाना ने उन्हें क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट में अपनी तरफ से खेलने के लिए बुलाया। तब से वह हिंदू जिमखाना के लिए खेलते रहे, बाद में उसके अध्यक्ष भी रहे। १९३१ में सिडनहम कालेज की क्रिकेट टीम के कैप्टेन के रूप में उन्होंने नार्थकोर्ट चैलेंज शील्ड तथा रहीमतुल्लाह चैलेंज कप जीतकर अपने फार्म में होने का सबूत दिया। उसी वर्ष इंग्लैंड जाने वाली क्रिकेट टीम में उन्हें शामिल किये जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन अंदरूनी राजनीति के कारण उनका नाम ऐन मौके पर कट गया। दो वर्ष बाद १९३३-३४ में, जब इंग्लैंड टीम भारत खेलने आयी, तो उन्हें पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। उस टेस्ट में उन्होंने छह पारियों में यद्यपि कुल १७८ रन ही बनाये, लेकिन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण का सिक्का इंग्लैंड टीम पर जमा दिया था। एम०सी०सी० (इंग्लैंड) टीम के कप्तान डी०आर० जार्डिन, विजय से कुछ इस तरह प्रभावित हुए कि उनकी तारीफ करते हुए कहा, "कमाल का खेलता है यह लड़का। इसने जिस तरह से हमारी तेज एवं बंपर गेंदों का मुकाबला किया है, उससे यह कतई नहीं लगता कि यह इसका पहला टेस्ट मैच है। इसे महान खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता।"

जार्डिन की भविष्यवाणी उन्होंने दो वर्ष बाद ही सही साबित कर दी, १९३६ में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट खेल कर। मुश्ताक अली के साथ द्विशतकीय भागेदारी (२०३रन) में उन्होंने ऐसे शानदार स्ट्रोक लगाये कि १९३९ में 'विजडेन' ने वर्ष के पांच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में उनको भी शामिल किया। दस वर्ष बाद १९४६ में 'क्रिकेट एनुअल' ने जब विश्व के पांच महान बल्लेबाजों की सूची प्रकाशित की, तो उसमें भी विजय मर्चेन्ट का नाम था। १९४६ तक उन्होंने २,३८५ रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। १९४६ में इंग्लैंड में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में अपनी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया था।

उन्होंने प्रथम श्रेणी के मैचों में ७ शतक बनाये। उनका रन औसत ७४.५३ रहा। उन्होंने सभी १० टेस्ट मैच (इंग्लैंड के विरुद्ध—१९३३-३४, १९३६ तथा १९४६) खेले और १८ पारियों में ८५९ रन (औसत ४९.७२) बनाये। इनमें तीन शतक भी थे।

रणजी ट्राफी चैंपियनशिप में उनकी बल्लेबाजी आज भी बेमिसाल मानी जाती है। १९४३ में महाराष्ट्र के विरुद्ध बंबई टीम के लिए ३५९ रन (नाट आउट) सहित कुल तीन पारियों में ५३३ रन तथा १९४४ में सात पारियों में ६०७ रन (औसत १०३.२२) बनाये। रणजी ट्राफी की कुल ४७ पारियों में उन्होंने १६ शतक सहित ३६३९ रन (औसत ९८.३५) बटोरे।

उन्होंने २२ वर्ष की क्रिकेट जिंदगी में कुल २१५ पारियां खेलीं। ४१ पारियों में वह नाट आउट रहे और १२,५८२ रन (४२ शतक, ४९ अर्द्धशतक) बनाये, जिनमें सर्वश्रेष्ठ स्कोर एक पारी में ३५९ रन (नाट आउट) रहा। उनका रन औसत ७२.३१ रहा। विश्व में रन औसत की दृष्टि से उनकी गणन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद दूसरे नंबर पर की जाती है।

विजय हर तरह के स्ट्रोक खेलने में माहिर थे (उन्हें 'स्ट्रोक प्लेयर' भी कहा जाता था), लेकिन उनके 'लेट-कट' और 'हुक' का जवाब नहीं था। दरअसल 'लेट-कट' विजय की ही ईजाद थी, जिसे बाद में गुंडप्पा विश्वनाथ ने अपनाकर श्रेष्ठतम बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त किया। इंग्लैंड के भूतपूर्व टेस्ट खिलाड़ी ट्रेवर वेली का कहन था—"जब वह गेंद पर स्ट्रोक लगाते या हुक करते, तो क्षेत्ररक्षक समझ ही नहीं पाते थे कि गेंद कहां और किस रफ्तार से जा रही है। साउथ हेड में हुए टेस्ट में तो उन्होंने अपना विश्वप्रसिद्ध लेट-कट इस खूबसूरती से लगाया था कि हममें से कुछ तो समझे कि वह अब बोल्ड ही हो जायेंगे, पर हम लोग गलतफहमियों में रहे और विजय एक-के बाद-दूसर रन बटोरने में मशगूल रहे।"

समाजसेवा: क्रिकेट से अवकाश लेने के बाद वह समाज सेवा, क्रिकेट कमेंट्री आदि से जुड़ गये। हर रविवार को ठाकरसी ग्रुप द्वारा रेडियो पर प्रस्तुत 'क्रिकेट विद विजय मर्चेन्ट' कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि अंग्रेजी न जानने वाले लोग भी दोपहर के दूसरे सारे कार्यक्रम रोक कर उसे सुना करते थे। बोलने के लिए न तो वह स्क्रिप्ट तैयार करते थे और न ही कोई दूसरी तैयारी। माइक के सामने आते ही वह इस तरह धाराप्रवाह बोलने लगते थे जैसे क्रिकेट के इनसाइक्लोपीडिया हों। इसकी चर्चा करने पर वह मुस्करा कर कह बैठते, "क्रिकेट मेरी जिंदगी है, आत्मा है, सांस है। क्या सांस लेने के लिए भी कोई तैयारी करनी पड़ती है?"

उन्हें न तो पद, कुरसी और अधिकारों का मोह था और न ही सम्मान, अलंकरण एवं पुरस्कारों का। समाज सेवा उनकी कमजोरी थी और इसके लिए रात-बिरात उनके दरवाजे हर आम आदमी के लिए खुले रहते थे। इसीलिए मौत की खबर सुनते ही सार काम-काज छोड़कर अंधी प्रमिला पाटोले जिसका उन्होंने कन्यादान किया था, अपने पति सुनील के साथ दौड़ी-दौड़ी उनके घर आयीं और उनके शव लिपट कर रोने लगी थीं।

—रवींद्र श्रीवास्त

]

अचानक

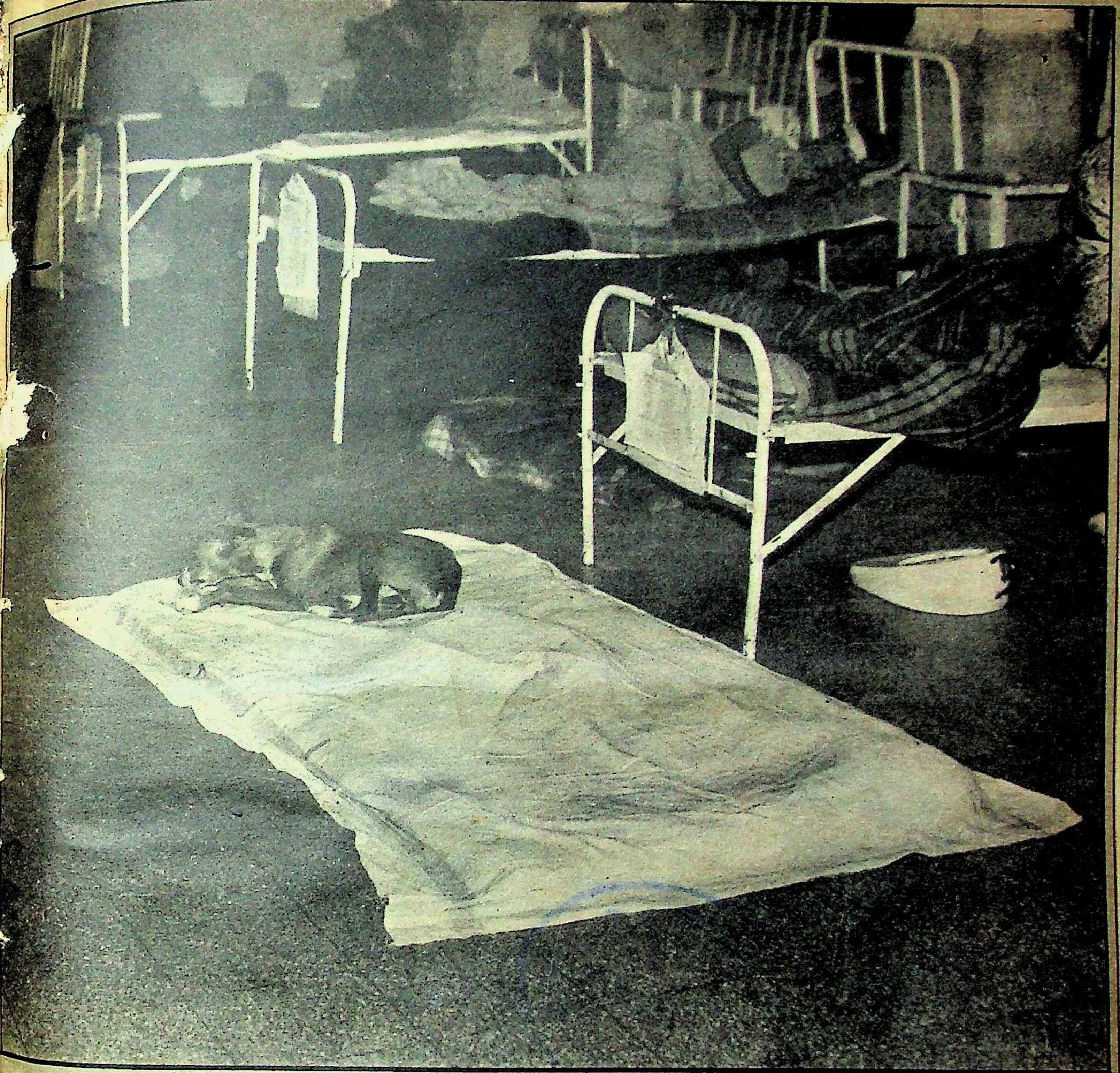

सफाई पर जोर देनें के लिए अक्सर कहा जाता है कि कुत्ता भी जहां बैठता है, वहां सफाई करके बैठता है। अस्पतालों में तो सफाई की और भी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए सफाई की प्रेरणा के लिए इस अस्पताल के प्रबंधकों ने वार्ड में कुत्ते को ससम्मान स्थान दे दिया है। अब कोई कहे कि ऐसी लापरवाही के कारण ही अकसर अस्पतालों से नवजात शिशुओं को कुत्ते उठा ले जाते हैं या इन कुत्तों से मरीजों में संक्रामक रोग फैल सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाये! वैसे प्रत्येक जीव के प्रति दया, सहिष्णुता और मनुष्य तथा कुत्तों में सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए ऐसी अस्पतालों की जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। भगवान की दया से ऐसे 'आदर्श' अस्पताल हमारे देश में कोई एक-दो नहीं। आप ऐसी उदात्तता के नजारे अधिसंख्य अस्पतालों में देख सकते हैं—क्योंकि २१वीं शताब्दी में प्रवेश के समय तक हमें सारे देश को स्वस्थ बनाना है।

छाया : नितिन पोपट

सुनील मनोहर गावस्कर

पिछला पखवारा क्रिकेट में दिलचस्पी रखनेवालों के लिए उतार और चढ़ाव का रहा। एक हस्ती ने विदा लिया और दूसरा महत्वपूर्ण हो गया। लगभग डेढ़ दशक तक अपने क्रिकेट जीवन की लंबी पारी खेलने के बाद गावस्कर बिना आउट हुए क्रिकेट की दुनिया से अलविदा कर लिए यानी उन्होंने प्रथम श्रेणी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दिलीप वेंगसरकर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुन लिए गये हैं। एक, महान पारी खेलकर मैदान से गया, तो दूसरा जिम्मेदारी भरी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतार दिया गया है।

सुनील मनोहर गावस्कर यानी लिटिल मास्टर यानी रन मशीन यानी सनी के भले ही संन्यास लेने से भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया हो, पर गावस्कर की उपलब्धियां कभी भी समाप्त नहीं होंगी। जब भी क्रिकेट की चर्चा होगी—गावस्कर के बिना पूरी नहीं होगी। गावस्कर ने क्रिकेट के खेल की बुलंदियों को स्पर्श करते हुए जितने कीर्तिमान स्थापित किये हैं, नहीं लगता कि कोई दूसरा उन बुलंदियों तथा कीर्तिमानों की बराबरी भी कर पाये।

अपने क्रिकेट कैरियर को 'जीवन का सर्वथा अविस्मरणीय और सुखद काल' बतानेवाले गावस्कर ने सबसे ज्यादा १२५ टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने १०६ मैच लगातार खेले। २१४. पारियां खेलकर उन्होंने ३४ शतक की मदद से सर्वाधिक १०,१२२ रन बनाये। गावस्कर ५८ बार शतकीय साझेदारी भी निभा चुके हैं। गावस्कर ने तीन बार एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया था।

संन्यास लेते-लेते गावस्कर ने अपनी दो इच्छाओं को सुंदर जामा पहनाया जब क्रिकेट के 'मक्का' लार्ड्स मैदान पर उन्होंने शतक बनाया और रिलायंस विश्व कप में न्यूजीलैंड के विरुद्ध विश्व कप में पहला शतक बनाया। गावस्कर ४७ टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, जिसमें भारत ने आठ टेस्ट जीते और नौ में भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा।

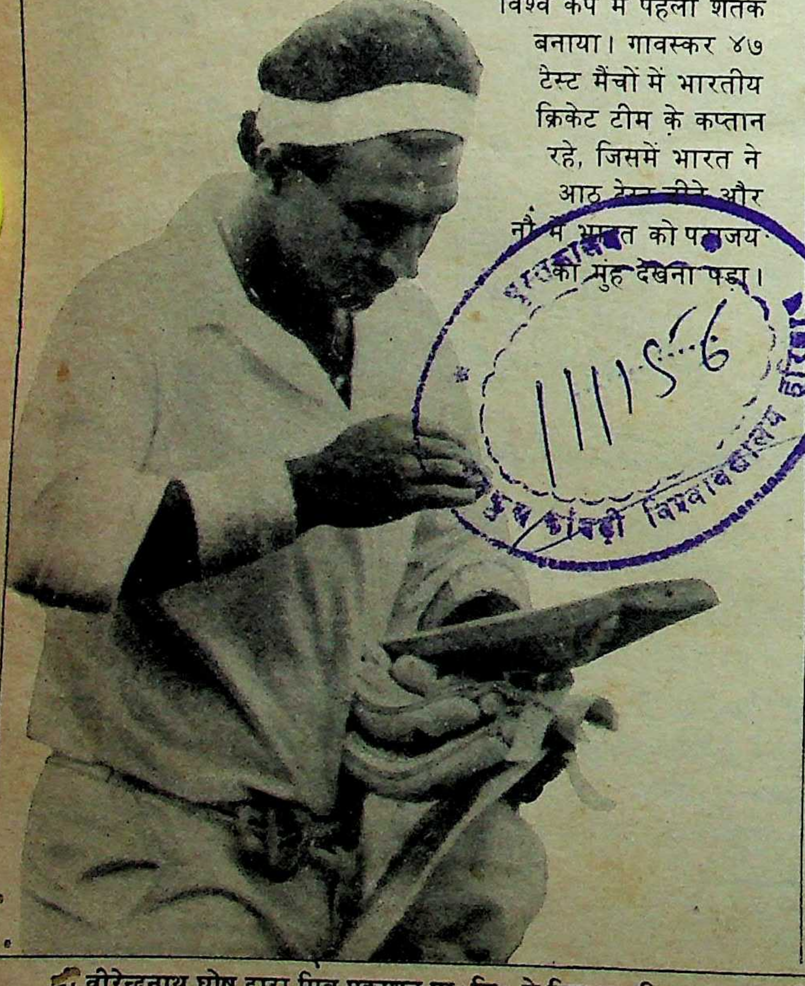

पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

खेल मैदान के बाहर भी अलंकरणों को प्राप्त करने में गावस्कर का अपना कीर्तिमान है। उन्हें १९७७ में 'अर्जुन पुरस्कार' और १९७९ में 'पद्मभूषण' से सम्मानित किया गया। १९८० में उनका नाम विजडेन के पांच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी था।

गावस्कर ने क्रिकेट केवल खेला ही नहीं, बल्कि उसे शब्दों में भी बाधा। अब तक गावस्कर ने चार किताबें— 'सनी डेज', 'आइडल्स' 'रंस एंड रुइंस' और 'वन डे वंडर्स' लिखी हैं। गावस्कर ने संपादन-क्षेत्र में भी खाता खोला है। कई वर्षों तक उन्होंने 'इंडियन क्रिकेटर' पत्रिका का संपादन भी किया।

दिलीप बलवंत वेंगसरकर

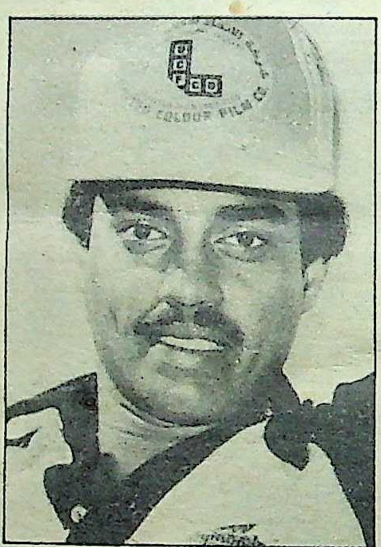

रिलायंस विश्व कप की दावेदारी से भारत क्या बाहर हुआ कि कपिल देव की कप्तानी पर प्रश्नचिह्न लग गया। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मिजाज की खबर रखनेवालों का दावा था कि कपिल देव की कप्तानी गयी। और वास्तव में नवंबर माह कपिल देव के लिए दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि पहले रिलायंस विश्व कप के सेमी फाइनल में भारत, इंग्लैंड से हार गया और दूसरे, कपिल की जगह दिलीप वेंगसरकर को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुन लिया गया।

२९ वर्षीय दिलीप बलवंत वेंगसरकर भारतीय क्रिकेट टीम के २३वें कप्तान चुने गये हैं। इसे
संयोग ही कहा जायेगा कि १
में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज
क्रिकेट टीम के साथ अपने क्रि
जीवन की शुरुआत करनेवाले
दिलीप वेंगसरकर वेस्टइंडीज
खिलाफ भारत का नेतृत्व करें

वेंगी और कर्नल के ना
पुकारे जाने वाले दिलीप
वेंगसरकर को यह सम्मान प्र
हुआ है कि वह राष्ट्रीय टीम
नेतृत्व अपनी राज्य टीम का
नेतृत्व करने से पहले ही कर
हैं। वेंगसरकर को रिलायंस
पूर्व ही बंबई टीम का कप्तान
बनाया गया था। वेंगसरकर
पिछले वर्षों में जिस तरह से
बल्ले से रनों को निकाला
है—उसी के चलते चयनकर्ता
उनके प्रति आकर्षित हुए, तभी
पहले उन्हें रिलायंस विश्व कप
रवि शास्त्री के स्थान पर
उपकप्तान बनाया गया और
दावेदारों को पीछे रखकर उन्हें
भारत का कप्तान चुना गया।
ऐसे समय में भारत का नेतृत्व
स्वीकार कर रहे हैं जब भारत
बल्लेबाजी विश्व में सर्वश्रेष्ठ
जा रही है।

दिलीप वेंगसरकर ने
तक ९५ टेस्ट मैचों में ५९५
बनाये हैं, जिनमें १५ शतक
शामिल हैं। उन्होंने ९७ एक
दिवसीय मैचों में २८०६ रन
बनाये हैं। दिलीप वेंगसरकर
पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जि
लार्ड्स में लगातार तीन शतक
बनाये हैं।

१६ अप्रैल, १९८७ को
क्रिकेट की बाइबिल कही
जानेवाली 'विजडन अलमानक
संस्करण में दिलीप बलवंत
वेंगसरकर को पिछले पांच व
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामि
किया गया था। विजडन में स
पाने वाले वेंगसरकर १२वें
भारतीय खिलाड़ी हैं। वेंगसर
को १९८७ में 'पद्मश्री' से भी
सम्मानित किया जा चुका है

भारतीय बल्लेबाजी की
रीढ़ समझे जाने वाले वेंगसर
अब भारतीय क्रिकेट टीम के
रीढ़ हो गये हैं। अब परीक्षा है
एक अच्छे बल्लेबाज के कप्ता
की।

—दिनेश

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

Compiled
1959-1980

111156